

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन

- खादी और ग्रामोद्योग कमीशन एक विधिकीर्तित संस्था है, जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम (१९५६ के ६१ वें) के मन्त्रालय अधिनियम १९५६ में हुई। इसका काम है अपने अन्तर्गत चलनेवाले १५ ग्रामोद्योगों के लिए योजना बनाना, संगठन करना तथा उनके विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। स्थापना होने पर इसने भूतपूर्व अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का कार्य अपने हाथ में लिया। कमीशन के पांच सदस्य हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव हैं। इसके सलाहकारी खादी और ग्रामोद्योग मण्डल में ४८ सदस्य हैं। कमीशन साधारण-तया इस सलाहकारी मण्डल की राय से कार्य करता है।
- कमीशन के अन्तर्गत खादी के अतिरिक्त ये ग्रामोद्योग हैं अनाज तथा दालों का प्रशोधन, तेल घानी, ग्रामीण नर्म, कुटीर दिशालाल, गड-स्थाण्डमागी, ताउ-गुड, अग्राय तेल तथा साबुन हाथ कागज, ग्रामीण कपटारी, मधुमक्खी-पालन, रेशा, बटुंगीरी तथा लोहारगीरी, गाद तथा मिथेन गैस का उत्पादन व उपयोग और चूना पत्थर तथा उसके उत्पादन।
- कमीशन के कार्यक्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन का कार्य स्वयम् करने, उनके लिए सहायता तथा प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त ये कार्य भी मुख्य रूप से सम्मिलित हैं खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन-कार्य में लगे कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उन्हें अपनी महकारी समितियाँ बनाने में प्रोत्साहन देना।
- कमीशन खादी तथा ग्रामोद्योगी वस्तुओं के उत्पादकों को सप्लाय करने के लिए कच्ची सामग्री तथा औजारों का सग्रह भी करता है। खादी तथा ग्रामोद्योगी उत्पादकों के बेचने की व्यवस्था करने का कार्य भी कमीशन के जिम्मे है।
- कमीशन को खादी तथा ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाली प्रविधियों के विषय में अनुसन्धान कराने तथा उसे प्रोत्साहन देने और खादी तथा ग्रामोद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए सुविधाएँ प्रस्तुत करने का कार्य भी सौंपा गया है।

दशम वर्ष • जनवरी १९६४ चतुर्थ अंक



दण्डिता का अभिशाप	-विवेकानन्द	२६९
खादी व ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में सहकार समस्या का मूल	-उत्तरगाराय न डेवर	२७३
खादी और ग्रामोद्योगों की प्रासंगिकता	-वैकुण्ठ ल. मेहता	२७६
भारत की अर्थ-व्यवस्था में सर्वेशियों का स्थान	-शुशील चन्द्र चौधरी और गधुनाथ गिरी	२८०
आय वितरण पर एक दण्ड	-विद्या सागर महाजन	२९२
आदिवासीयों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर	-दत्तात्रेय ना. वान्देकर	३००
वालुद महाल विकास योजना एक विवेचन	-विमल शाह	३०३
विचार-विमर्श		३०६
पाली में एकमुश्त कार्यक्रम	-माखन लाल मट	३०७
रेशम उद्योग व रेशम अनुसंधान	-कमल बनर्जी	३१४
सामाजिक अनुसंधान की भूमिका	-श्रीमशुन्दर यशवन्त	३१७
ग्राम्य जीवन में स्थिरता और परिवर्तन	-शुभाष चन्द्र शरव्दार	३१९
पुस्तक समीक्षा		
एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड उक्तानामि डेवलपमेण्ट इन इण्डिया, राफ्ट प्रकाशनी और जेम्स जे. स्पेगलर द्वारा सम्पादित।		३२६
पाठकों के विचार		३३०

सम्पादक . सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोद्योग', इलाहाबाद, बम्बई-५६ में मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थ शास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोद्योग', इलाहाबाद रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। टेलिफोन नं. ५७१४५०।

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर लिया गया हो।

वार्षिक शुल्क ₹ ५० रुपये, एक प्रति . २५ रुपये पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए अस्सिस्टेण्ट प्रकाशक आफिसर (काश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोद्योग', इलाहाबाद रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६।

इस अंक के लेखक

उछरंगराय नवलशकर डेबर	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष ।
बंकुण्ठ लल्लूभाई मेहता	—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।
सुशोल चन्द्र चौधरी	—नयी दिल्ली स्थित केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय में आर्थिक और सांख्यिकी मलाहकार ।
रघुवीर गिरी	—नयी दिल्ली स्थित केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय के आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय के मलाहकार ।
विद्या सागर महाजन	—कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सांख्यिकी मण्डल के औद्योगिक सांख्यिकी विभाग में सम्बद्ध ।
वन्नात्रेय नाथोबा चान्द्रेकर	—बम्बई राज्य के भाषापूर्ण उप-मंत्री और प्रसिद्ध तथा अनभरी समाजसेवी ।
विमल शाह	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अहमदाबाद स्थित मघन क्षेत्र योजना (गुजरात) के विकास अधिकारी ।
माखन लाल भट	—कलकत्ता विद्यानगर (गुजरात) स्थित कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र में वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक ।
कमल बनर्जी	—खारा (पश्चिम बंगाल) से प्रकाशित मुंशिदाबाब समाचार के सम्पादक ।
तंडलम् सोमसुन्दर यशवत	—मद्रास विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र अनुसन्धान केन्द्र में वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता ।
सुभाष चन्द्र सरकार	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग तथा जागृति के सम्पादक ।

दरिद्रता का अभिशाप

विवेकानन्द

भारत को अगर कोई आशा है तो वह एक मात्र उसकी साधारण जनता से

* * *

क्या तुम्हें मनुष्य से प्यार है ? ईश्वर की खोज में कहां भटक रहे हों ? क्या ये सारे गरीब, दुखी और निर्बल ही ईश्वर नहीं हैं ? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते ? गंगा के तीर पर रहते हुए भी जल के लिए कुआँ खोदना कैसा ?

* * *

हमारे दैनिक स्वभाव की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब दूसरे भी वैसा ही करने को अभिप्रेरित होंगे।

प्रकृति में वैषम्य होते हुए भी सबको समान अवसर मिलने चाहिए—या किसी को ज्यादा और किसी को कम भी मिले तो भी निर्बल को सबल से अधिक अवसर मिलने चाहिए।

* * *

मैं किसी ऐसे ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवाओं के आँसू न पोंछ सके या अनाथों के मुँह तक रोटी का टुकड़ा न पहुँचा सके। सिद्धान्त चाहे कितने भी ऊँचे क्यों न हों, दर्शन कितना भी तर्कयुक्त क्यों न हो, जब तक वह पौधियों और रुढ़ियों में बन्द है, मैं उसे धर्म नहीं कह सकता। ईश्वर को कहाँ ढूँढ़ रहे हो ? क्या ये सारे गरीब, दुखी और निर्बल ही ईश्वर नहीं हैं ? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते ?

* * *

कल एक महिला जेलखाने के सुपरिण्टेण्डेण्ट से मिलने आयी थी। वे उस जेलखाने को जेलखाना न कह कर सुधारगृह कहते हैं। मैंने अमेरिका में यह सबसे

बड़ी चीज देखी। वहाँ रहनेवालों के साथ कितना सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उनमें सुधार लाकर समाज के लिए उपयोगी बना कर उन्हें किस प्रकार वापस भेजा जाता है। यह कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत है ! इन सब को देखिए तब विश्वास होगा। और तभी भारत के गरीबों और दलितों की याद आते ही मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। उन्हें कोई अवसर नहीं, बचने की गुंजाइश नहीं, ऊपर उठने का कोई सहारा नहीं। भारत के उन गरीबों, दलितों एवम् पतितों का कोई मित्र नहीं, कोई सहारा नहीं। वे उठ नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न करें। दिन-प्रति-दिन वे डूबते ही जा रहे हैं। क्रूर समाज के थपेड़ों को वे महसूस तो करते हैं, पर यह नहीं जानते कि ये थपेड़े उन पर कहाँ से बरसाये जा रहे हैं। वे इस 'सत्य' को भूल चुके हैं कि वे भी इन्सान हैं। और इसीलिए गुलामी भोग रहे हैं।

* * *

मैं महात्मा उसी को कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए द्रवित होता है, नहीं तो वह धूर्तत्मा है, जब तक करोड़ों इन्सान भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार समझता हूँ जो उनके बूते यानी खर्च पर पढ़ा-लिखा है पर उनकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। मैं उन लोगों को क्रूर कसाई समझता हूँ जो गरीबों को चूस कर शान से अकड़ते चलते हैं और उन करोड़ों के लिए, जो भूख कंकाल बन चुके हैं, कुछ नहीं करते।

* * *

इस उर्वर देश में, जहाँ जल का कोई अभाव नहीं और स्वयम् प्रकृति अन्य देशों से हजार गुना अधिक धन

और फल प्रदान करती है, तुम्हारे पेट में अन्न नहीं, तन ढाँकने को वस्त्र नहीं। धन-धान्य से परिपूर्ण इस देश में जहाँ की वस्तुओं के प्रसार के साथ दुनिया के अन्य देशों में सम्यता का प्रसार हुआ, तुम इनके अधःपतन की अवस्था तक पहुँच गये। तुम्हारी हालत कत्ते से भी बदतर हो चुकी है। फिर भी, तुम अपने वेदों और वेदान्तों की गरिमा का राग अलापते फिरते हो।

* * *

जो राष्ट्र स्वयम् के लिए महज भोजन और वस्त्र की भी व्यवस्था न कर सके, जीने के लिए दूसरों पर आश्रित रहे, तो वह जीता ही क्यों है? इस समय अपने धार्मिक ख्यालान उतार फेंको और सबसे पहले अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को तैयार हो जाओ।

* * *

सैकड़ों वर्षों से अपने दिमाग पर जमे हुए अध-विश्वास का भार लेकर बैठे-बैठे, सैकड़ों वर्षों से भोजन की अस्पृश्यता और स्पृश्यता पर बकवास में शक्ति का व्यय करते-करते, युगों की लगातार सामाजिक क्रूरता से कुचली हुई मानवता को लेकर आज तुम कहाँ हो? और अब क्या कर रहे हो? हाथों में किताबें लेकर समुद्र के किनारे घूमना, यूरोपीय दिमागी बकवासों की पुनरावृत्ति और महज तीस रुपये की किरानागिरी करने या ज्यादा से ज्यादा वकील बनने की आत्म-प्रवचना—नये भारत की महत्वाकांक्षा—और फिर, प्रत्येक विद्यार्थी के पैरों पर सर पटक-पटक कर रोटी मागनेवाले भूखे बच्चों का समूह। क्या समुद्र में इतना जल नहीं है कि तुम तुम्हारी किताबें, गाउन, विश्वविद्यालय की उपाधियाँ और सब कुछ उसी में डूबो दो?

* * *

आलस्य, नीचता और अहमन्यता ने सारे देश को आच्छादित कर रखा है। क्या कोई प्रखर व्यक्ति इस अवस्था को देख कर शांत रह सकता है? क्या उसकी आँखों में आँसू नहीं आ जायेंगे? मद्रास, बम्बई, पंजाब, बंगाल जहाँ-कहीं भी मैं देखता हूँ, जीवन के चिन्ह कहीं

दिखायी ही नहीं पड़ते। तुम समझते हो कि तुमने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। किन्तु क्या बकवास तुमने पढ़ा है? दूसरों के विचारों को विदेशी भाषा से दिलों में उतार कर और किमी विश्वविद्यालय की डिग्री लेने के लिए माथा-पच्ची करके तुम समझते हो कि तुम पढ़े-लिखे हो। लानत है तुम्हारे ऊपर। क्या यही शिक्षा है? तुम्हारी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? किराना-गिरी करना या कफन-खसोट वकील बनना या ज्यादा-से ज्यादा डिप्टी मजिस्ट्रेट बन जाना जो किरानागिरी का ही दूसरा रूप है। उससे तुम्हारा या तुम्हारे देश का क्या भला होनेवाला है? अपनी आँखें खोलो और देखो, इस भारत देश में, जिसकी धन-सम्पत्ति की गाथाएँ गायी जाती हैं, अन्न के लिए कितना करुण क्रंदन उठ रहा है। क्या तुम्हारी शिक्षा इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है? कभी नहीं।

पाश्चात्य विज्ञान की मदद लेकर तुम जमीन खोदो और खाद्यान्न पैदा करो, दूसरों की नीच बटाईदारी के जरिये नहीं, बल्कि पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से अपने प्रयासों के जरिये उत्पादन के नये क्षेत्रों का पता लगाओ। इसीलिए मैं इन देशवासियों को पुरजोर काम करने का उपदेश देता हूँ, ताकि वे अपने लिए खाद्यान्न और वस्त्र उत्पादित करने में सक्षम हो जायें। खाद्यान्न और वस्त्र की कमी और उसकी चिंता में व्यग्र, हमारे देश का सर्वनाश हो चुका है।

इसका क्या उपाय है, तुम्हारे पास? अपने धर्म ग्रन्थों को गंगा में फेंक दो और जनता को पहले खाद्यान्न और वस्त्र प्राप्त करने के उपाय सिखलाओ। तभी तुम्हें उन्हें धर्म ग्रन्थ सुनाने के अवसर मिल सकेंगे। पुरजोर काम करने की प्रवृत्तियों को उभाड़ कर अगर उनके भौतिक अभावों की पूर्ति नहीं की गयी, तो आध्यात्म-वादी शब्दों को कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए, मैं कहता हूँ कि पहले स्वयम् के अन्दर आत्म शक्ति को ऊपर उठाओ और तब उसके प्रति यथा शक्ति आत्म जनता का विश्वास प्राप्त कर, उन्हें सबसे पहले यह सिखाओ कि

वे खाद्यान्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुस्त होकर बैठने का समय नहीं है। कौन जानता है, मौत का झपट्टा कब किस पर पड़े।

* * *

और, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अन्याचार और जल्म बन्द करे। कितनी हास्यास्पद स्थिति में हमें ला दिया गया है। अगर कोई भगी कही भगी के रूप में आता है तो मानो गजब हो गया। लेकिन वही भगी अगर अपने मर किमी पादरी के हाथ में पानी डलवा कर और एक कोट पहन कर, चाहे उसके तार-तार ही क्यों न हो गये हों, किमी रूडीवादी हिन्दू के घर में भी आता है तो मैं देखता हूँ कि कोई उसे कुर्मी देने या उससे हाथ मिलाने में इन्कार करने का साहम नहीं करता। इससे बढकर और दुर्भाग्य क्या होगा ?

* * *

क्या वह भी कोई धर्म है जो गरीबों के दुःख दूर न करे और मनुष्य को ईश्वर के रूप में न बदल दे ? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि हमारा धर्म अपने नाम के अनुरूप है ? हमारा धर्म तो 'छूओ मत' है, सिर्फ छूओ मत, छूओ मत ! भगवान बचाय ! ऐसा देश, जिनके नेतागण पिछले दो हजार वर्षों के अन्दर सिर्फ इसी की विवेचना करते आ रहे हों कि दाहिने हाथ से भोजन करना या बायें हाथ से, दाहिने हाथ से पानी पीना है या बायें हाथ से, तो फिर अगर वह देश सर्वनाश को प्राप्त न होगा तो हमारा कौन होगा ?

आओ, इन्सान बनो ! उन पुरोहितों को जो प्रगति के विरोधी हैं, निहाल बाहर करो, क्योंकि वे बदल नहीं सकते, उनका हृदय कभी महान् नहीं होगा। वे सदियों के अंध-विश्वास और अन्याचार की पैदाइश हैं। पहले उनकी पुरोहिनी खत्म करो। आओ, इन्सान बनो। अपने दरबो से निकल कर विशाल दुनिया को देखो। देवो अन्य राष्ट्र कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें इन्सान से प्यार है ? क्या तुम्हें अपने देश से प्यार है ? अगर हाँ, तो आओ, ऊँची और बेहतर चीज के

लिए हम सवर्ष करे। पीछे मत देखो, अगर कोई अपना रोता-चिल्लाता हो, तो भी मत देखो। पीछे नहीं आगे देखो।

* * *

अपने देश के गरीब लोगों को अन्न के लिए जब तरसते देखता हूँ तो मन में आता है कि पूजा के सारे नैवेद्य उठा कर फेंक दू और चरित्र और साधना के बल से गाँव-गाँव घूम कर धनिकों से धन माग कर सग्रह करूँ और गरीबों की सेवा में जीवन अर्पित कर दू।

* * *

अफसोस ! देश के गरीबों की खोज-खबर लेने-वाला कोई नहीं है। ये ही लोग देश की रीढ़ हैं, ये ही मेहनत करके खाद्यान्न पैदा करते हैं। ये गरीब भगी और मजदूर अगर एक रोज के लिए भी काम बन्द कर दे, तो शहर तबाह हो जाय। पर, उनके साथ किसी को हमदर्दी नहीं, उनके दुःखों में उन्हें सात्वना देनेवाला भी कोई नहीं। क्या इतना उदार और दयावान इस देश में कोई है ? यहाँ तो सिर्फ 'मत छूओ' वाले ही रहते हैं। इन सारी कुरीतियों को दूर करो। मैं कभी-कभी जब 'मत छूओ' की दिवारों को तोड़ देने की आवश्यकता महसूस करता हूँ तो शीघ्र बाहर निकल कर ऊँची आवाज में डेरता हूँ— 'सारे गरीब, दुखी, दलित और कमजोर लोगों, आओ,' और उन सबको श्री रामकृष्ण के नाम पर एक करना चाहता हूँ। जब तक वे नहीं उठेंगे, मैं नहीं उठेगी। हम उनके लिए अन्न, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था न कर सके, तब हमने किया क्या ? हाय-हाय ! वे दुनिया को कुछ भी नहीं जानते, और इसीलिए दिन-रात काम करके भी अपने लिए भोजन और वस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग, उनकी आँखें खोले। मैं दिन के प्रकाश की तरह देखता हूँ कि उनके और मेरे बीच एक ही ब्रह्म है। एक ही शक्ति सब में मौजूद है। फर्क सिर्फ आत्म प्रकाश में है। अगर सारे शरीर में रक्त प्रवाहित नहीं हो पाता, तो लकवा मार जाता है, पहले एक अंग में, फिर सारे शरीर में। उस शरीर का

फिर क्या किया जा सकता है ? उस मत्स्य को जान लो।

* * *

मेरे जीवन का एक मात्र उद्देश्य यही रहा है कि एक यत्र चलाया जाय, जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वार तक अच्छे विचार पहुँचाये, और तब नर-नागियों को अपने भाग्य का फैसला कर लेने दो। उनको यह समझाओ कि हमारे और अन्य देशों के पुरुषों ने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किये हैं। उन्हें खाम कर यह बनाना है कि दूसरे अब क्या कर रहे हैं, और फिर उन्हें अपना निर्णय स्वयम् लेने दो। हमें समस्त रामायनिक पदार्थ एक जगह रख देने हैं, प्रकृति स्वयम् उन्हें ठोस बनायेगी। कठिन मेहनत करो, स्थिर रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। काम करो, मैं देर-सबेर आ ही रहा हूँ। एक ही उद्देश्य सामने रखो, "धर्म को बिना नुकसान पहुँचाये सर्व साधारण को ऊपर उठाना।"

याद रखो कि राष्ट्र ओपडियो में रहता है। पर अफ-सोस ! उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे

आधुनिक सुधारवादी विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए व्यस्त हैं। दर-असल मैं प्रत्येक सुधारवादी कार्य का हिमायती हूँ, पर किसी राष्ट्र का भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितनी विधवाओं को फिर से पति मिल गये, बल्कि आम जनता के हालात पर। क्या तुम उनमें जागृति ला सकते हो ? क्या उनकी आध्यात्मिक प्रकृति को बिना किसी तरह का नुकसान पहुँचाये, उनका खोया हुआ व्यक्तित्व उन्हें वापस दिला सकते हो ? क्या तुम अपनी समानता, स्वातंत्र्य, कर्म और शक्ति की भावनाओं के सम्बन्ध में घोर पाश्चात्यवादी बने रहने के साथ-साथ धार्मिक, सांस्कृतिक तौर पर और अतः प्रेरणा से मूलतः हिन्दू रह सकते हो ? यह करना है और हम करेंगे। तुम सब इसे करने के लिए पैदा हुए हो। स्वयम् में विश्वास रखो, महान विश्वास रखो, महान विश्वास ही महान कार्यों का जनक है। मदा आगे बढ़े, गरीबों और दलितों के लिए मरने तक महानु-भूति रखे, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ●

आधुनिक व्यक्ति के जीवन में निश्चयात्मक कारक तकनीको में खोजा जाना चाहिए। हम नयी तकनीको के युग में प्रवेश कर चुके हैं और वे न सिर्फ जीवन के आर्थिक बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी घुस गयी हैं। भूतकाल में भी प्राविधिक प्रगति हुई थी, परन्तु हमारे आज के युग की यह एक विशिष्टता बन गयी है कि तकनीको ने अपनी अल्लर्निहित शैतानी शक्ति को प्रकट कर दिया है और वह आदमी को अपना गुलाम बनाने को उद्यत है।

—मैक्सिको के प्रो. लैरोयो द्वारा मैक्सिको में अर्टीथ इंटर-नेशनल काँग्रेस ऑफ फिलासफी में दिये गये भाषण से।

खादी व ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में सहकार : समस्या का मूल

उद्धरंगराय न. देबर

खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, उसे प्रोत्साहन देने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उन्हें रोजगारी प्रदान करने, तकनीकों में सुधार लाने, सुत्कारों व अन्य कारीगरों का सामाजिक तथा आर्थिक दर्जा निर्मित करने के लिए काम करना होगा और यह देखना होगा कि एक ऐसी अवस्था आये कि वे अपना काम कारीगरों के सगठनों को सौंप सकें। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन जिस सहकारी सगठन पर जोर देता है उससे जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह स्वरूप मानव मानव के बीच समानता, एक सामूहिक आवाज का होना और प्रत्येक सदस्य में अभिक्रम विकसित करने के लिए अवसर की प्राप्ति सुनिश्चित करता है।

हमें पहले और सबसे पहले, गांधीजी के सगठनात्मक तन्त्र की तह तक पहुँचना चाहिए। कैसे तो वे इतने सगठन खड़े कर सकें और किस तरह इतने विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ काम कर सकें? इसका उत्तर हम नध्य में निहित है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियाँ सभी उनके लिए एक मुख्य साध्य के साधन थीं, साध्य था एक भय रहित, गतिशील मानवता-सत्य तथा अहिंसा की ओर आगे बढ़ रही मानवता-रूपी ठोस आधार पर भारत के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में पुनः प्राण फूँकना। उन्होंने सोचा—और वास्तव में बहुत सही सोचा—कि आदमी को जब तक मौका नहीं मिलता वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। अतएव सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियाँ उनके लिए भारतीय पौरुष और नारीत्व के निर्माण हेतु व्यावहारिक मार्ग थे।

व्यक्तित्व विकास

गांधीजी को जो लक्ष्य अथवा साध्य प्रिय था, जिसके लिए उन्होंने काम किया उसे आगे बढ़ाना खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की जिम्मेवारी है। यह काम तभी हो सकता है, जबकि खादी और ग्रामोद्योग जो अवसर उपस्थित करते हैं उनका उक्त प्रकार की

मानवता का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाय। गांधी विचार के अनुसार काम केवल पारिश्रमिक भर प्रदान करने के लिए नहीं है, उसके मुताबिक मानव के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वह एक साधन है। इसलिए काम का विवेचन, उससे रुपये-पैसे के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक की शब्दावली में ही नहीं किया जाना चाहिए। उसका सम्बन्ध वह जिस प्राविधिक ज्ञान का विकास करता है उससे, जो वित्तीय प्रतिष्ठा अथवा साख की पैठ वह जमाता है उससे और प्रबन्ध तथा सगठन में जिस अभिक्रम को वह प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, उससे होना चाहिए।

पूँजीवादी व्यवस्था पारिश्रमिक दे सकती है, प्राविधिक ज्ञान का विकास कर सकती है, लेकिन प्रतिष्ठा और व्यवस्थापकीय अभिक्रम के लिए कामगार को उन व्यक्तियों पर निर्भर करना पड़ेगा जो पूँजी के मालिक हैं अथवा जिनका उस पर नियन्त्रण है। नौकरशाही कार्य-कुशलता दे सकती है। वह दूसरे व्यक्तियों को अपने प्राविधिक ज्ञान का विकास करने में सहायता देगी। लेकिन वह तिजोरी की चाबी और सामरिक महत्व की बातों पर से अपना नियन्त्रण कभी हाथ से नहीं निकलने देगी। प्रबन्ध नियन्त्रण तो साम्यवादी

र्यो में बड़े समाजवादी देशों तक में भी चन्द व्यक्तियों के हाथ में ही रहेंगे। यदि कोई गणना है जिसमें साधारण में साधारण व्यक्ति भी यह आशा कर सके कि जीवन में उसका जो भी दर्जा हो, विवेक और रुपये-पैसे की दृष्टि में उसके जो भी साधन-स्रोत हों, मानव होने के नाते उसे प्रत्येक दिशा में अपना अभिक्रम विकसित करने की स्वतन्त्रता तथा अवसर मिलेंगे तो, वह मार्ग गांधीजी की स्वतन्त्र, भय-मुक्त और अहिंसक समाजवादी कल्पना में निहित है।

सूतकार और बुनकर तथा धोबी व पिजारे अपनी वर्तमान कठिनाइयों के मध्य भी कमीशन, राज्य मण्डलों और सस्थाओं में काम करनेवाले हम सबसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम उन्हें सम्पत्ता के लाभ प्रदान करवायेंगे। यही प्रत्यामिता (ट्रस्टीशिप) के माने हैं। एक प्रत्याम-धारी न तो जनता के पैसे में चिपक कर घाती उम पर छाती टेक कर ही बैठता है और न तो वह सदैव के लिए प्रबन्ध नियंत्रण अपने हाथ में रखने के लिए उसे हड़प ही लेता है। वह इसके लिए अवसर की तलाश करता है कि जिनके लिए वह काम करता है वे यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध अभिक्रम, प्राविधिक ज्ञान और साख हासिल करने में समर्थ हों।

इस प्रकार कमीशन, राज्य मण्डलों और सस्थाओं के समक्ष एक चौहरा कर्तव्य है

- १ काम प्रदान करने के लिए काम करना है,
- २ तकनीकी में सुधार करने के लिए काम करना है,
- ३ सूतकारों, बुनकरों आदि का आर्थिक व सामाजिक दर्जा निर्मित करना है, और
४. वैसी स्थिति लाने के लिए काम करना है कि अपना काम उनके हाथ में सौंपा जा सके।

सहकारिताएँ क्यों ?

सूतकार, बुनकर आदि उत्पादन करने के लिए जिस प्रकार का संगठन चाहते हों उसका चुनाव कर

सकते हैं। इस सम्बन्ध में वे पंजीकृत सस्था या सहकारी समिति अपना सकते हैं। यदि सस्थाएँ उक्त चौहरे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं तो कमीशन इस मन्दर्भ में कोई सख्ती नहीं बरतना चाहता। सस्थात्मक स्वरूप के बारे में यदि कमीशन सहकारी संगठन का सुझाव देता है तो वह इसलिए कि उसे यह विश्वास है कि इस सम्बन्ध में उससे बहुत लाभ होगा।

सर्व प्रथम, सहकारी व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से एक स्वस्थ स्वरूप है। द्वितीय, इससे नौकरशाही का विस्तार नहीं होता। तृतीय, यह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है। चतुर्थ, सहकारी समिति यदि बहुत बड़ी नहीं हुई तो सदस्यगण व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाने में समर्थ बनते हैं और इसलिए साक्षरता की भावना विकसित करने में भी। पंचम, एकसम आधार पर उधार और प्राविधिक सुविधाएँ प्रदान अथवा प्राप्त करने के लिए वह एक सुविधाजनक साधन बन सकता है। इनके अतिरिक्त और भी लाभ हैं। लेकिन जितने भी लाभ हैं उनमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वरूप मानव-मानव में समानता, एक सामूहिक आवाज का होना और गांधीजी प्रत्येक सदस्य में जो अभिक्रम देखना चाहते थे उसका विकास सुनिश्चित करना है। इन सब बातों को देखते हुए ही कमीशन सहकारी विभाग के विस्तार पर जोर देता है।

लोक विश्वास

लेकिन किसी दूसरे आर्थिक संगठन के समान हमारे सामने भी सवाल यह है कि लोगों को इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में दिलजमी कैसे करवायी जाय, उन्हें विश्वास कैसे दिलवाया जाय। सम्पर्क स्थापित करके और प्रात्यक्षिकों की व्यवस्था करके यह काम किया जा सकता है। अभिक्रम, प्राविधिक ज्ञान और साधन-स्रोतों के निर्माण में प्रोत्साहन देने हेतु इस सस्थात्मक स्वरूप की क्षमता बढ़ाने के लिए यदि हम दो अन्य कदम उठा सके तो इस विचार-प्रसार में सुविधा होगी।

प्रथम, कार्य-क्षम सहकारी सगठनों के बारे में परिपूर्ण जानकारी देना हमारे लिए लाभप्रद होगा। द्वितीय, पजीकृत सस्थाओं का राज्य स्तरीय सगठन की स्थिति से विकेन्द्रीकरण करने के लिए हमें प्रक्रिया यानी विधि तैयार करनी और मुझानी पड़ेगी कि किस प्रकार क्रमिक रूप से वे अपने काम का विकेन्द्रीकरण करके उत्पादन कार्य कारीगरों की सहकारी समितियों को सौंप सकती हैं। वे अपने काम का विकेन्द्रीकरण कर सकती हैं और उत्पादन-तंत्र कारीगरों की सहकारी समितियों को सौंप सकती हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेवा सुविधाएँ कम नहीं की जाती वरन् बढ़ायी जानी हैं। यह भी देखना होगा कि इस 'लाइन' में काम करते आ रहे इतर कारीगरों की दिलचस्पी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है।

अतएव मैं यह सुझाना चाहूँगा कि कमीशन की सहकारी परामर्शदात्री समिति यथा सम्भव शीघ्र ही इस पहलू पर सर्व सेवा मध्य की खादी समिति से विचार-विमर्श करें। इसके लिए नमूने के तौर पर चन्द अलग-अलग प्रकार की सहकारिताएँ बनाना आवश्यक होगा, जिनके खण्ड और जिला स्तरीय सहकारी मध्य हों, खण्ड और/या जिला स्तरीय सहकारी

सेवा सस्थाएँ हो, जिनका खण्ड अथवा जिला स्तर पर पजीकृत सस्थाओं के साथ सजीव सम्बन्ध हो। सस्थात्मक स्वरूप जितना एक समान होगा खादी और ग्रामोद्योगों के हित में वह उतना ही अच्छा होगा।

उपयुक्त कर्मचारी

द्वितीय प्रश्न है उपयुक्त कर्मचारी तैयार करने का। सस्थाओं को यह देखना होगा कि जिस काम का उन्होंने सृजन किया है, उसमें उपयुक्त व्यक्तियों की कमी के कारण कोई बाधा न आने पाये। सबसे बड़ा सवाल तो है उपयुक्त प्राविधिक कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धि का, जो ईमानदारी के साथ रुपये-पैसे सम्बन्धी काम सम्हाल सके। कमीशन, राज्य मण्डल व सस्थाओं, सभी को एक साथ बैठ कर ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा। योजना बना ली जाती है तो, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि कमीशन आवश्यक वित्त प्राप्त करने में समर्थ होगा। मानवीय समानता और स्वतन्त्रता के आधार पर अभिक्रम निर्मित करना खादी आन्दोलन का एक उद्देश्य है और सहकारी विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

बम्बई ३ दिसम्बर १९६१

यद्यपि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गुजराती एक औसतन भारतीय से कुछ अच्छी हालत में हैं, तथापि इन दोनों की आमदनी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। उपलब्ध प्रमाणों से इस बात का संकेत मिलता है कि खुले आम पूर्ण तथा अर्द्ध-बेरोजगारी का काफी बाहुल्य है। हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार ४२ प्रति शत ग्रामीण और ५ प्रति शत शहरी श्रम-शक्ति परिपूर्णतः बेरोजगार है: ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य-कारी जन-संख्या के एक-दशांश लोगों के पास उस वस्तु जबकि वे काम कर सकते हैं, इतना काम नहीं है कि वे अपने को परिपूर्ण रूप से व्यस्त रख सकें।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात : नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

खादी और ग्रामोद्योगों की प्रासंगिकता

चकुण्ठ ल. मेहता

“भारतीय जनता को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के अवसर” प्रदान करने के लक्ष्य की पूर्ति—जिसकी व्याख्या तृतीय पंच वर्षीय योजना में की गयी है—ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को बहुमुखी बनाये और उस राह पर औद्योगिक उत्पादनों का विकास किये बना, जोकि आय तथा आर्थिक अधिकार दोनों का ही संकेन्द्रण होने से रोकते हैं तथा ग्रामीण और शहरी आय के बीच का अन्तर कम किये बिना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय योजनाओं में खादी और ग्रामोद्योगों को भावात्मक आधार पर नहीं बल्कि ‘जांच और मूल्यांकन समितियों’ के निष्कर्षों व सिफारिशों की बिना पर शामिल किया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आन्दोलन में लगे हम कार्यकर्ता आजकल अच्छी सोहबत में हैं। कई ऐसे राजनीतिज्ञ तथा प्रचारक हैं, जो आयोजन के दर्शन में विश्वास नहीं करते अथवा यह दोषारोपण करते हैं कि हमारा आयोजन असफल रहा है। अतः एक रविवारीय समाचार पत्र के एक ही अंक के कालमों में हाल ही में दो लेखों का प्रकाशित होना—‘खादी और ग्रामोद्योग असफल क्यों रहे हैं’ (व्हाई खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज हैंव फेल्ड) जिसमें लेखिका का नाम दिया है तथा सम्पादकीय कालम में लिखा गया ‘खादी दर्जन’ (दि फिलॉसफी ऑफ खादी)—कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जो लोग देश के गरीब से गरीब लोगों तक उपयोगी कार्यों के माध्यम से जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित प्रयास की निन्दा करते हैं, वे हमारे योजित विकास के मूल उद्देश्य के प्रति ही असवेदनशील हैं, जिसकी व्याख्या तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वाक्य में इस प्रकार की गयी है, “मुख्य उद्देश्य निश्चय ही भारतीय जनता को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर प्रदान करना है।”

रोजगारी-उन्मुख ग्रामीण औद्योगीकरण

इस उद्देश्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती—जैसा कि दो वर्ष पूर्व ‘भारत में आयोजित अर्थ-

व्यवस्था की दिशा’ पर आयोजित गोष्ठी में कहा गया था—जब तक कि सर्वाधिक प्राथमिकता काम चाहनेवाले हर व्यक्ति को काम देने की व्यवस्था करने को न दी जाय। तदनुसार योजनाधिकारियों के सामने सबसे बड़ा काम है आबादी के एक बड़े भाग के लिए रोजगारी की व्यवस्था करना, ताकि वे कम से कम न्यूनतम भोजन की आवश्यकता तो पूरी कर सकें। इसके लिए हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को बहुमुखी बनाना आवश्यक है और उस राह पर औद्योगिक उत्पादनों का विकास करके—जोकि आय तथा आर्थिक अधिकार दोनों का ही संकेन्द्रण होने से रोकते हैं—ग्रामीण और शहरी आय के बीच का अन्तर कम करना पड़ेगा।

जैसा कि गोष्ठी ने व्यक्त किया था कि इसकी प्राप्ति छोटी-छोटी पारिवारिक इकाइयों अथवा उत्पादकों द्वारा चलायी जानेवाली मध्यम इकाइयों के जरिये उद्योग में स्व-रोजगार का विकास करके हो सकती है। इस प्रकार के विकेंद्रित औद्योगीकरण के अन्तर्गत एक ऐसे ग्रामीण औद्योगिक विकास के सगठनार्थ प्रयास करना होगा, जिसमें अधिकतम लोगों को रोजगारी मिल सके, विशेष कर यदि कच्चे माल के रूप में स्थानीय साधन उपलब्ध हों और उत्पादन मुख्यतः देहात के लोगों की आम जरूरतें पूरी करने हेतु उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हो।

इस कार्य के लिए अपनायी जानेवाली तकनालाजी का स्तर अनिवार्यतः ऐसा करना होगा कि वह विनियोजित पूँजी की प्रति इकाई पर काफी लोगों को रोजदारी दे सके। अतः उसे ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आनेवाले गाँवों में उपलब्ध पूँजी और श्रम के विशेष मिश्रण के अनुरूप समज्जित करना होगा। दुर्भाग्यवश देश के अधिकांश भागों में बहुत अधिक पूर्ण तथा अर्ध-बेकारी है। अतः इसका मुकाबला करने के लिए निम्न स्तरीय तकनालाजीवाले उद्योगों के लिए जोकि न्यून आय कर सकते हैं, उपदान की व्यवस्था तब तक करनी ही होगी, जब तक कि क्षेत्र में कृषि के अलावा अन्य कार्यों में रोजगारी विस्तार के साथ ही आय का स्तर भी ऊँचा नहीं उठे।

तकनालाजी का स्तर

यह यथा सभव औद्योगिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण की ओर सकेत करता है। दस प्रकार का विकेन्द्रीकरण मानवीय उपागम के समानरूप है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने शुद्ध स्वदेशी पर जोर दिया और वस्त्र उत्पादन—हमारी एक प्राथमिक आवश्यकता—के क्षेत्र में खादी जिनका प्रतिनिधित्व करती है। कुछ दिनों पहले दक्षिण भारत में एक स्थान पर भाषण देते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने यह विचार प्रकट किया बताया कि योजना का लाभ समाज के कमजोर वर्गों को मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए गांधीजी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माणकार्य के तौर-तरीकों का अपना उपयोगी होगा।

भावात्मक आधार पर नहीं

खेद की बात है कि ऊपर बताये गये लेखों में इस विवेकशील दृष्टिकोण को दृष्टि ओझल कर दिया गया है तथा यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि भावनात्मक कारणों में ही खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम को हमारी पंच वर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया है। यह न तो योजना आयोग के साथ

ही न्याय है और न भारत सरकार के साथ ही, कम से कम द्वितीय तथा तृतीय पञ्च वर्षीय योजनाओं में इनमें से कोई भी सिर्फ भावनात्मक स्थान रखनेवाले कार्यक्रम के लिए शायद ही निधि देने को तैयार होता। यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि जब प्रथम पंच वर्षीय योजना बनायी गयी तब कोई अनुभव नहीं था। परन्तु उसके बाद की जो दो योजनाएँ बनीं तब तो कार्यान्वयन के परिणाम सामने थे। सच तो यह है कि दोनों ही अवसरों पर योजना आयोग के समक्ष 'जाच और मूल्यांकन समितियों' के निष्कर्ष और सुझाव थे। यह मान लिया गया है कि विकास प्रस्तावों को योजना में शामिल करने के पूर्व उन पर अच्छी तरह विचार कर लिया गया था।

परिचय

यदि खर्च के सही आँकड़े जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, प्रस्तुत किये गये होते तो कार्यक्रम के साथ न्याय होता। जैसा कि लेखों में बताया गया है कि पिछले दस वर्ष में खादी और ग्रामोद्योगों पर १ अरब ७९ करोड़ रुपये खर्च हुए, यह सही नहीं है। फिर, जैसा कि लेखों में अन्यत्र बताया गया है कि प्रथम पंच वर्षीय योजनावधि में ८७ करोड़ रुपये वितरित हुए, यह सख्या भी सही नहीं है। सन् १९५३-५४ से १९६२-६३ तक कुल १ अरब ४५ करोड़ रुपये वितरित किये गये और प्रथम पंच वर्षीय योजना में तो परिव्यय सिर्फ ८ करोड़ ३० लाख रुपये ही था। पिछले दस वर्ष की अवधि में कुल वितरित रकम में से १९६३-६४ के आरम्भ में ४७ करोड़ ९६ लाख रुपये ऋण के बाकी थे, जोकि संचालन पूँजी और उत्पादन के लिए दिये गये थे और इनमें से अधिकांश खादी के मद में दिया गया था। बाकी रकम छूट (रिबेट) और उपदान (मन्सिडी), सभी स्तरों पर दिये जानेवाले प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा उत्पादन और बिक्री संगठन पर खर्च हुई।

उस अवधि में खादी का उत्पादन हर वर्ष बढ़ता गया है और दस वर्ष पहले जो उत्पादन था आज वह मान गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही रोजगारी में भी वृद्धि हुई है, योजना में इस कार्यक्रम को शामिल करने के समय में अब तक करीब पाँच गुनी वृद्धि हुई है। वृद्धि के अनुपातों में अन्तर अंश परम्परागत चरखा चलानेवाले स्तंकारों को मिली पूरी रोजगारी और अंश अम्बर चरखे की बड़ी उत्पादकता दर्शाता है। कार्यक्रम में शामिल ग्रामोद्योगों के उत्पादन में इसी प्रकार की, परन्तु इसमें कुछ कम उल्लेखनीय, वृद्धि हुई है। इन उद्योगों में, हाथ कागज उद्योग अथवा कुटीर साबुन उद्योग को मुख्यतः छोड़कर, अनिरिक्त लोगो को रोजगारी देने के बदले पूर्णतर रोजगारी दी गयी है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था जिम बीमारी में पीड़ित है वह है कृषि और कुटीरोद्योग दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फैली अर्थ बेकारी।

इसमें मुख्य बात यह है कि माल भर पूरे दिन का काम नहीं मिलता। जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नौवें दौर में बताया गया है, दो करोड़ लोगो के पास प्रति दिन एक घण्टा या उससे कम का काम है और चार करोड़ लोगो के पास प्रति दिन चार घण्टा या उससे कम का। करोड़ों लोगो को लाभदायक रोजगारी नहीं मिलने के कारण ही ग्रामीण आय का स्तर नीचा है। अतः यह एक स्पष्ट और विशिष्ट लाभ है कि परम्परागत उद्योगों में लगे लोगो के लिए पूरे समय का काम प्राप्त होता है, साल के अधिकांश भाग में जो बेकार रहते हैं उनके लिए गैर-मौसम में काम उपलब्ध होता है और आंशिक कर्मियों के लिए अधिक सघन कार्य प्राप्त किया जाता है।

पूर्ण रोजगारी

जिनके लिए इस कार्यक्रम के जरिये काम प्राप्त होता है, यदि उनकी औसत आय प्रति वर्ष १०० रुपये के आसपास है तो इसमें कुछ उपहासपूर्ण नहीं

है। यह मानना होगा कि इन लोगों के लेखक इस नथ्य से अवगत नहीं है कि जब पिछली कृषि जाच समिति ने सर्वेक्षण किया था तो श्रमिकों की औसत आय १०० रुपये में कुछ कम ही पायी गयी थी। गमाज के कमजोर वर्गों की आय के विषय में डा राम मनोहर लोहिया के कथन पर जब हाल ही में लोकसभा में बहस हुई थी तो डा लोहिया के उत्तर में श्री गुलजारीलाल नन्दा ने बताया था कि नितल श्रेणी के दस प्रति शत लोगो का दैनिक खर्च शहरा में ५३ आना और गाँवों में ४३ आना है। यह बहुत ही दुःखद अवस्था है कि जिम परम्परागत चरखे पर प्रति दिन मुश्किल से औसत चार आने अर्थात् २५ नये पैसे की आय होती है, आज भी उमे देश के कई भागों में बहुत बड़ी सख्या में कत्तिने, जोकि घोर गरीबी में दिन बिता रही है, चला रही है तथा अपना रही है। इसके विम्नार की सीमा निर्णय इसलिए है कि इससे तैयार की गयी खादी की बिक्री में कठिनाइया आती है।

शक्ति का उपयोग

इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण आय में खादी और ग्रामोद्योगों के योगदान को आकना चाहिए, न कि कारखाना उद्योग में लगे चन्द लोगो की प्रति माह सौ रुपये की आय की पृष्ठभूमि में। इन औद्योगिक कर्मियों की सख्या देश की कुल आबादी के एक प्रति शत से भी कम है। दस वर्ष की सम्पूर्ण योजनावधि में ऐसे कर्मियों की सख्या ९ लाख ९८ हजार ही बढ़ी है जबकि उनके पीछे कुल निवेश ८ अरब १७ करोड़ रुपये बढ़ा है। इसके मुकाबले अभी खादी और ग्रामोद्योगों में लाभदायक रोजगारी पानेवाले लोगो की सख्या करीब २० लाख है, यह एक प्रशंसनीय कार्य है, विशेष कर इसमें लगी बहुत कम पूजी को देखते हुए। रोजगारी की दृष्टि से योजित कार्यक्रम के विभिन्न विभागों के कार्य के अध्ययन से पता लगेगा कि खादी और ग्रामोद्योगों का अंशदान कितना मूल्यवान रहा है, उनमें कितनी क्षमता है।

कार्यक्रम के अधिकारीगण जिन परम्परागत तकनीकों

को अपनाये हुए हैं तथा तकनीको में सुधार का जो वे विरोध करते हैं, उसके विषय में बहुत टीका की जाती है। सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है शक्ति के इस्तेमाल न करने का। कार्यक्रम से सम्बन्धित लोगों ने समय-समय पर इस विषय में स्पष्टीकरण किया है। यदि शक्ति के इस्तेमाल से कुछ कारीगर प्रत्यक्ष रूप में रोजगारी खो देते हैं तो ऐसी शक्ति का इस्तेमाल इससे बेकार होनेवाले लोगों को कोई अन्य काम दिये बिना होने देना समाज के लिए घातक होगा। फिर, पहले और आज भी शक्ति का इस्तेमाल सामान्यतः स्व-रोजगार प्राप्त कारीगर को मजदूर बना देने और श्रम के शोषण का विस्तार करने तथा आय का केन्द्रीकरण करने में किया जाता रहा है। ऐसी अवस्था में शक्ति के इस्तेमाल को अपनाने देना समाज विरोधी कार्य होगा। जैसा कि दि अदर अमेरिका * में श्री माइकेल हैरिंगटन (Michael Harrington) कहते हैं, “यदि बिना सामाजिक प्रगति के प्राविधिक प्रगति होती है तो स्वयमेव तुरन्त ही मानवीय दुःख-दर्द, गरीबी बढ़ने ही वाली है।” परन्तु जहाँ इस तरह के परिणाम की आशंका नहीं है, वहाँ कार्यक्रम के अधीक्षकों ने उच्च तकनालाजी अपनाने का विरोध नहीं किया है।

मूल्य में कमी करने के उपाय

चाहे कुछ भी सुधार किये जायें, यह ध्यान में रखना चाहिए कि श्रम-प्रधान उत्पादन कार्यक्रम में लागत मशीनी उत्पादन से अधिक ही रहेगी। उदाहरण-स्वरूप, शक्ति करघा का उत्पादन हाथ करघे से सस्ता होगा, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति ५ अथवा ६ व्यक्तियों का काम करता है। तथापि, यदि सामाजिक नीति के तौर पर हाथ करघों को शक्ति करघों में परिवर्तित न करने का निर्णय किया जाता है तो, हाथ करघे का वस्त्र इसी तरह के शक्ति करघा वस्त्र से महँगा ही बना रहेगा। ग्रामोद्योगों के अधिकांश उत्पादनों पर यह बात लागू होती है, और विशेष कर हाथ कताई

पर, जिसमें श्रम-विस्थापन हाथ बुनाई से कहीं बहुत अधिक होगा। अम्बर चरखे के आविष्कार का स्वागत हुआ है, क्योंकि इसके उपयोग से उत्पादकता बढ़ती है। तथापि, इसके आगमन से उत्पादन खर्च में कमी नहीं आयी है, क्योंकि जान-बूझ कर इस चीज को प्राथमिकता दी गयी है कि प्राविधिक प्रगति का लाभ उपभोक्ताओं के बदले कारीगरों को मिले। सूतकारों और बुनकरों की क्षमता या कार्य-कुशलता सुनिश्चित हो जाने के बाद उत्पादन केन्द्रों में तथा उनके आसपास मूल्य भी कम किये जा सकते हैं। सब प्रयास निश्चय ही इस ओर निर्दिष्ट होने चाहिए, विशेष कर वैसी तकनीकों और औजारों को अपना कर जोकि उत्पादन का स्तर ऊपर उठाते हों।

स्वदेशी की भावना

अगर यह सुनिश्चित करना है कि हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में विकेन्द्रित उत्पादन के जो सामाजिक लाभ हैं प्राविधिक प्रगति का उन पर उल्टा प्रभाव न पड़े तो गति थोड़ी धीमी होगी। जब तक परिवर्तन होता रहता है यह राज्य का कर्तव्य है—चूँकि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय योजना का अभिन्न अंग माना गया है—कि वह उत्पादन के लिए जरूरी आर्थिक सहायता दे। समाज को भी, सरकार से अलग रूप में, कुछ वैसी जिम्मेदारी लेनी है, जैसी उसने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में देशी उद्योगों के उत्पादनों को अपना सहयोग देकर निभायी है और आज भी निभा रहा है। गांधीजी ने प्रायः यह बताया कि खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगी उत्पादन शत प्रतिशत स्वदेशी है। स्वदेशी की व्याख्या करते हुए उन्होंने इसे पड़ोसी धर्म कहा था, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वदेशी का आग्रह करनेवाला जहाँ-कहीं भी सम्भव होगा स्थानीय उत्पादनों को प्राथमिकता देकर अपने पड़ोसियों की मदद करने की कोशिश करेगा, भले ही वे माल कुछ घटिया किस्म के हों अथवा अन्य स्थानों पर बने माल के मुकाबले महँगे हों। पिछले बारह वर्षों के आयोजन में कई विभागों में प्रगति होने के बावजूद, यदि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था की मौजूदा कमियों को दूर करना चाहते हैं तो हमें स्वदेशी भावना अपनानी ही चाहिए।

* माइकेल हैरिंगटन दि अदर अमेरिका (पावर्टी इन दि युनाइटेड स्टेट्स), पेगिन बुक्स, लंडन, १९६३, पृष्ठ १८७, मूल्य ३ शिलिंग ६ पेन्स।

भारत की अर्थ-व्यवस्था में मवेशियों का स्थान

सुशिल चन्द्र चौधरी और रघुवीर गिरी

मवेशी न केवल फल पैदा करने में मदद देते हैं, बल्कि दूध और दुग्धोत्पादन के रूप में पौष्टिक भोजन भी प्रदान करते हैं। देश के कुल पशु-उत्पादन में मवेशियों का योगदान करीब ८८ प्रति शत है। पशु-पालन के सम्बन्ध में एक विवेकपूर्ण नीति यह होगी कि अमिताभ्ययी गायों तथा अन्य मवेशियों का वन्ध्यकरण करके जन्मानुपात और जो पशु पैदा हो उनकी अच्छी मार-सम्भाल करके मृत्योनुपात कम करते हुए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में हानि होना कम किया जाय।

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। देश की लगभग ७५ प्रति शत आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए या तो सीधे रूप में कृषि और अन्य ग्रामीण काम-धंधों में लगी हुई है अथवा उन पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय में करीब आधा हिस्सा खेती तथा अन्य सम्बद्ध उद्योगों का है। इसमें से तकरीबन ४१ प्रति शत प्राप्ति विशुद्ध खेती तथा उसकी सहायक गति-विधियों से होती है, सात प्रति शत पशु-पालन और दुग्ध उद्योग से एवम् शेष वन्य कामों व मत्स्य-पालन से। कृषि विभाग में फसल बोने काटने तथा इस काम की सहायक गतिविधियों के बाद आय का दूसरा प्रमुख स्रोत है पशु-पालन और दुग्ध काम। वास्तव में किसान का सामाजिक दर्जा साधारण तौर पर या तो इस बिना पर आका जाता है कि उसके पास कितनी जमीन है अथवा वह कितनी भूमि जोतता है या फिर इस आधार पर कि उसके पास कितने पशु हैं अथवा खेती करने के लिए वह कितने हल चलाता है।

भारतीय कृषि में मवेशी

विभिन्न प्रकार के पशुओं में मवेशियों* का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण केवल यही नहीं है कि कुल पशु-धन में उनकी संख्या मोटे तौर पर दो-तिहाई है, बल्कि यह भी कि खेती से उनका बहुत निकट सम्बन्ध है और किसान की समृद्धि में वे अनेक रूपेण योगदान

* इस लेख में मवेशी शब्द का अर्थ भैंस-भैंसों को छोड़ कर है। लेख में उनका वर्णन अलग से किया गया है।

देते हैं। हल चलाने, खेतों में खाद डालने, सिंचाई के लिए पानी खींचने, उत्पादन ढोने, उत्पादन को खेत से फटकने-बुहारने की जगह तक और फिर वहाँ से बाजार ले जाने तथा गन्ना और तेल पेगाई के लिए क्रमशः कोल्हू व घानी चलाने जैसे सभी कृषि कार्यों के लिए खींचन-शक्ति प्राप्त करने के वे मुख्य स्रोत हैं। जब तक अमृत्य किसान अपने मामूली साधन-स्रोतों से छोटे-छोटे अलग-थलग खेतों में खेती करते रहेंगे और यह भी कि जब तक धान की खेती के लिए खेतों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करके पानी रोकने के लिए मेडबन्दी करते रहना पड़ेगा, तब तक इनमें से अनेक कामों में यात्रीकरण करने या लाने की बहुत सीमित गुंजाइश है। अधिकतम सम्भव सीमा तक यात्रीकरण करने के बाद भी भारत में कृषि-कार्यों के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने में ढोरो का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा।

मवेशियों की महत्ता तो इसी से समझी जा सकती है कि किसी फसल के उत्पादन में उनका कितना हाथ, योगदान है। देश के विभिन्न भागों में 'फार्म व्यवस्था' सबधी अध्ययनों से सकलित तालिका १ के आकड़ों से पता चलेगा कि कृषि-उत्पादन में मवेशियों और व्यक्तियों के श्रम का सापेक्षिक महत्व किना है तथा समग्र कृषि-लागत में उनका सम्मिलित योगदान कितना है।

तालिका १

चुनिन्दा क्षेत्रों में खेती की कुल लागत में मानवीय और पशु-शक्ति का योग

सर्वेक्षित क्षेत्र	सर्वेक्षण के अन्तर्गत मुख्य फसले	सर्वेक्षण काल	कुल कृषि खर्च में औसत प्रातिशत्य		
			जन-शक्ति	पशु-शक्ति	योग
सेलम व कोयम्बतूर (मद्रास)	धान, ज्वार व कपास	१९५४-५५ १९५६-५७	२० २	२२ ५	४२ ७
अकोला व अमरावती (महाराष्ट्र)	कपास, ज्वार व मूंगफली	" "	३१ ६	१८ ६	५० २
अहमदनगर व नासिक (महाराष्ट्र)	गेहूँ, ज्वार और बाजरा	" "	३५ ०	१९ ७	५४ ७
अमृतसर व फिरोजपुर (पंजाब)	गेहूँ व कपास	" "	२६ १	२२ ४	४८ ५
मेरठ व मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	गेहूँ व गन्ना	" "	२८.७	४१.८	७० ५
हुगली व २४ परगना (पश्चिम बंगाल)	धान तथा जूट	" "	४६ ३	७ ६	५३ ९
पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	धान व तम्बाकू	१९५७-५८ १९५९-६०	२१ ३	१० ६	३१ ९
सम्बलपुर (उड़ीसा)	धान	" "	३८ ०	२० ०	५८ ०

स्रोत . विभिन्न राज्यों में स्टडीज इन इकॉनॉमिक्स ऑफ फार्म मैनेजमेण्ट पर प्रतिवेदन; अर्थ और सांख्यिकी निर्देशालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

देश के विभिन्न भागों में फसलों की खेती पर जितना खर्च पड़ता है उसमें ३२ से ७० प्रति शत तक हिस्सा मानवीय और पशु-शक्ति का होता है। खेत और फसल पद्धति के अनुसार मानवीय श्रम तथा पशु-शक्ति का हिस्सा क्रमशः २० से ४६ और ८ से ४२ प्रति शत तक होता है। किमी फसल की खेती में जितनी आदा (इनपुट) होती है, उसमें पशु-शक्ति का योगदान जन-शक्ति के बाद सबसे अधिक है। इन आंकड़ों में कृषि उत्पादन के परिवहन और गन्ना तथा तेल पेराई में पशु-शक्ति का जो हिस्सा है, वह शामिल नहीं है। इस प्रकार भारतीय कृषि में उनके योगदान का एक आंशिक चित्र ही सामने आता है। पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में मवेशियों से प्राप्त शक्ति का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है, किन्तु एक अनुमान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि उनका योगदान तीन से पांच अरब रुपये के बराबर होता है।

फसल-उत्पादन में मवेशियों के योगदान की चर्चा करते समय व्यक्ति के विचार में जो दूसरा मद सामने आता है वह है उनके गोबर व मूत्र आदि से प्राप्त खाद, क्योंकि प्राणारिक द्रव्य का मिश्रण करने पर उससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। यद्यपि प्रमुख पोषकों के सम्बन्ध में कृत्रिम उर्वरकों से कमी पूर्ति हो जाती है, तथापि प्राणारिक खाद में एक लाभ यह है कि वह अनेक गौण पोषक तत्वों की पूर्ति

करते समय व्यक्ति के विचार में जो दूसरा मद सामने आता है वह है उनके गोबर व मूत्र आदि से प्राप्त खाद, क्योंकि प्राणारिक द्रव्य का मिश्रण करने पर उससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। यद्यपि प्रमुख पोषकों के सम्बन्ध में कृत्रिम उर्वरकों से कमी पूर्ति हो जाती है, तथापि प्राणारिक खाद में एक लाभ यह है कि वह अनेक गौण पोषक तत्वों की पूर्ति

कमती है और भूमि की भौतिक विशिष्टताएँ निर्मित कमती है। तीव्र जाग्रण (आक्मीडेशन) के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी में प्रागाग्निक द्रव्य सामान्यतः कम होता है। अतएव आसानी में घलने, पोषक तत्वों की तुल्य पूर्ति करने आदि के कारण रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर जोर देने के बावजूद मिट्टी में प्रागाग्निक द्रव्य पुनरापूर्ति करने और रासायनिक उर्वरकों के अनुपयुक्त उपयोग के फलस्वरूप मिट्टी में पैदा होनेवाले अनेक दोषों को दूर करने, उसे अच्छी अवस्था में रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ ही पूरक रूप में प्रागाग्निक खाद भी डालनी पड़ती है।

मवेशी न केवल फल पैदा करने में ही सहायक होते हैं, बल्कि वे दुग्ध तथा दुग्धोत्पादनों के रूप में शक्तिबद्ध भोजन भी प्रदान करते हैं। मवेशियों में प्राप्त ये उत्पादन जैविक दृष्टि से मूल्यवान वसा प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। शाकाहारियों के मामले में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। कुछ अनुपात में इन उत्पादनों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है और फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों को रोजगारी व जीविकोपार्जन का साधन प्राप्त होता है। डेरी फार्मिंग से उस भारतीय किसान को एक कीमती सहायक उद्योग की पूर्ति होती है,

जिसकी आमदनी बहुत कम होती है और खेती से उसे वर्ष के अधिकांश समय काम नहीं मिलता।

मवेशी खाल व हड्डियों जैसे अन्य महत्वपूर्ण उत्पादनों के भी स्रोत हैं। देश के द्रुत आर्थिक विकास के फलस्वरूप चर्मोद्योग में खालों की माँग बढ़ गयी है, जोकि इस उद्योग की बुनियादी कच्ची सामग्री है। इसके अतिरिक्त भारत के निर्यात व्यापार के भी वे महत्वपूर्ण अंग हैं। छोटी-बड़ी खालों (फर खाल सहित), चमड़े व चर्मोत्पादनों का ३४ से ४२ करोड़ रुपये तक का निर्यात होता है। इस सम्बन्ध में तालिका २ विस्तृत प्रकाश डालती है।

यदि मृत पशुओं की खालें एकत्रित करने के काम का आज की अपेक्षा अच्छा संगठन किया जा सके तो उक्त उत्पादनों से होनेवाली आमदनी और भी बढ़ सकती है।

राष्ट्रीय आय में योग

अब हम इस पर विचार कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न जाति के मवेशियों से प्राप्त उत्पादनों का क्या योगदान है। देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में पच वर्षीय रूप से की गयी पशु-गणनाओं से पशुओं की संख्या के सम्बन्ध में विश्वस्त आकड़े उपलब्ध हैं। ये गणनाएँ १९५१, १९५६, और १९६१ में कुछ

तालिका २

छोटी-बड़ी खालों, चमड़े व चर्मोत्पादनों का निर्यात मूल्य

(लाख रुपये में)

मद		१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३
छोटी-बड़ी खाले	११,२३.२	९,४५.८	८,२१.६	१०,८४.४
फर चर्म	३४.३	५५.९	५७.४	१६.८
चमड़ा	३०,४४.५	२४,८४.५	२५,३२.९	२२,५७.८
चर्मोत्पादन	१५.५	१२.४	१२.५	१७.४
योग	४२,१७.५	३४,९८.६	३४,२४.४	३३,७६.४

स्रोत मन्थली स्टेटिस्टिक्स ऑफ फोरेन ट्रेड ऑफ इण्डिया, और 'डिपार्टमेण्ट ऑफ कामर्सियल इण्टेलीजेंस एण्ड स्टेटिस्टिक्स'।

विशेष अच्छी तरह से हुई। उनसे विभिन्न प्रकार के पशुओं की सख्या के सम्बन्ध में व्यापक व विश्वस्त आकड़े प्राप्त हुए हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में उपलब्ध आकड़े इतने विश्वस्त नहीं हैं कि पशु-उत्पादनो का परिमाण कितना है। तदर्थ जौचो पर आधारित खाद्य और कृषि मन्त्रालय के मार्केटिंग और इन्स्पेक्शन निर्देशालय के बिक्री व्यवस्था सर्वेक्षण प्रतिवेदन दुग्ध तथा अन्य पशु-उत्पादनो के सम्बन्ध में कुछ अनुमान प्रस्तुत करते हैं। भारतीय कृषिक अनुसन्धान परिषद की कृषिक अनुसन्धान सांख्यिकी सस्था ने दुग्ध-उत्पादन तथा कुछ अन्य पशु-उत्पादनो का ठोस अनुमान प्राप्त करने के लिए प्रतिचयन तकनीक का विकास किया है, लेकिन इन उत्पादनो के सम्बन्ध में विश्वस्त अनुमान प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा इन तकनीको को अपनाया जाना शेष है। अन्य किसी प्रकार के अनुमानो के अभाव में भारत सरकार के मार्केटिंग और इन्स्पेक्शन निर्देशालय द्वारा प्रस्तुत अनुमानो का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय आय में परिमाण तथा मूल्य के रूप में विभिन्न प्रकार के पशु-उत्पादनो का क्या योगदान है, इस सम्बन्ध में आकड़े तालिका ३ में दिये गये हैं।

तालिका ३

प्रचलित मूल्यों के आधार पर १९५८-५९ में पशु-पालन से कुल आय में मवेशी-उत्पादनो का योग

मद	परिमाण	मूल्य (लाख रु में)	कुल आय में पशु- पालन का प्रातिशत्य
१. दुग्ध और दुग्ध-उत्पादन	दस हजार टन में		
(क) मवेशी व भैंस का दुग्ध	१९,१५५	७,५९,६०	६४५
(ख) अन्य	५६१	/	
२. गोबर			
(क) खाद	२२६	१,१३,६१*	९७
(ख) ईंधन व अन्य कामो के लिए	१२६	१,१३,६१*	९७
३. माँस व उसके उत्पादन			
(क) गाय व भैंस का माँस	१६७	१०,४०	०९
(ख) अन्य (माँस व माँस-उत्पादन)		८१,११	७०
	लाख की सख्या में		
४ मवेशी व भैंस-भैंसों की खाले	२१०	१५,०१	१३
५ भेड़-बकरियों की खाले	४५१	१३,८१	१२
६ ऊन और बाल		१३,३९	११
७ अण्डे व मूर्गी-पालन		२८,३६	२४
८ हड्डिया		१,३८	०१
९ स्टाक में वृद्धि		२४,४०	२१
	योग	१,१७,४६८	१०००

स्रोत (१) नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स - केन्द्रीय सांख्यिकी सगठन, सांख्यिकी विभाग; १९९१, (२) मार्केटिंग और इन्स्पेक्शन निर्देशालय - खाद्य और कृषि मन्त्रालय।

* मूल्यों में मवेशियो के गोबर की कीमत के अलावा अन्नावलियों, घास नली, पशु रक्कन, सर, टांगों, बेकार माँस आदि से प्राप्त खाद्य आदि का मूल्य भी शामिल है। गोबर व अन्य मद्दों का कुल परिमाण ५० लाख २५ हजार टन होगा।

मौस, छोटी खालो, ऊन, बाल तथा मूर्गी-पालन से प्राप्त उत्पादना के अलावा पशुओं से जितने उत्पादन प्राप्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में मवेशी प्रधान स्रोत हैं। पशु-उत्पादनों के मूल्य में करीब ८८ प्रति शत हिस्सा इन्हीं का होता है। पशु-पालन से जितनी आय होनी है उसका प्रायः दो-तिहाई हिस्सा दूध तथा अन्य दुग्धोत्पादनों का होता है और करीब पाँचवा हिस्सा गोबर का होता है। देश के कुल दुग्ध-उत्पादन में गायों व भैसों से करीब ९७ प्रति शत प्राप्ति होनी है (इसमें से ३९ प्रति शत का दूध के रूप में, ४६ प्रति शत का घी और मक्खन के रूप में तथा नौ प्रति शत का दही के बनीय एवम् चार प्रति शत में कुछ ऊपर का खोवे के रूप में इस्तेमाल होता है)। खाल उत्पादन के सम्बन्ध में भी मवेशी ही प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ यह स्मरण रहे कि देश में छोटी-बड़ी खालों के कुल उत्पादन में करीब ३२ प्रति शत हिस्सा मवेशियों से प्राप्त खालों का है।

एक सही कदम

देश के कुल गोबर उत्पादन का तकरीबन आधा हिस्सा, ईंधन का कोई वैकल्पिक स्रोत न होने की वजह से जलाया जाता है। अधिक उपज प्राप्ति के लिए रासायनिक उत्पादनों का अधिक उपयोग होता है। इस ज्यादा उपयोग के कारण मिट्टि में जो असंतुलन पैदा हो जाता है, उसे ठीक करने के लिए गोबर की खाद का भी अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता है। अतएव गोबर बचाने और उसका खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करना पड़ेगा। ईंधन के रूप में जलाने के लिए गोबर से गोबर गैस सयंत्र के जरिये अपेक्षाकृत सस्ती लगत पर गैस प्राप्त होती है। इससे गोबर के खाद तत्वों में भी कोई हानि नहीं होती। अतएव गोबर गैस सयंत्रों को लोकप्रिय बनाना देश के खाद तत्वों की बचत करने के लिए एक सही कदम है।

खालों के साथ ही, मृत तथा काटे गये पशुओं की हड्डियाँ एकत्रित एवम् प्रशोधित करने के लिए उपयुक्त

व्यवस्था के अभाव में पशु स्रोत से प्राप्त हो सकने-वाली काफी खाद की हानि होती है। इस सम्बन्ध में कुटीरोद्योगी आधार पर हड्डी चूर्ण उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे मवेशियों की हड्डियों का खाद के रूप में उपयुक्त उपयोग करने को प्रोत्साहन मिलेगा।

पशु-शव के उपयुक्त उपयोग, चर्म शोधन, चर्म कार्य व गैस उत्पादन और उसके इस्तेमाल हेतु चर्मोद्योग के लिए एक सर्वांगीण कार्यक्रम बनाया जा सकता है। हड्डी और मौस खाद, मिर्गो, खुरो तथा अन्य बेकार अंगों की खाद की पूर्ति, मूर्गी-पालन के लिए आमिष खाद्य, दूध-उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुओं को देने के लिए हड्डी-चूर्ण (बोन-मील), माबुन के लिए चर्बी तथा नी-फुट आयल एवम् मरेश की पूर्ति के लिए पशु-शव के उपयोग-कार्य को अधिक अच्छी तरह संगठित करने की आवश्यकता है। गैस सयंत्र के संचालन हेतु गोबर के अलावा पशु-शव की रद्दी चीजों व चर्म-शोधनालय के पानी से मिथेन गैस प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद गैस सयंत्र से गैस बनने के बाद बची रद्दी-गैस रहित-सामग्री का खाद्यान्नो तथा चारे की उपज बढ़ाने के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मवेशियों का संघटन

चूँकि भारतीय कृषि में मवेशियों का प्रायः बहुत बड़ा स्थान है इसलिए उनकी सख्या के सबध में आकड़े इकट्ठे करने के लिए पहले अनेक प्रयास किये गये। तथापि, विभिन्न राज्यों में पशु-चिकित्सालय तथा पशु-पालन और सेवा विभाग खोल कर देश में मवेशियों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार ने वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में ही कदम उठाये। पशु-धन के विकास के लिए कार्यक्रम बनाने और कार्यान्वित करने के लिए मवेशियों व अन्य पशुओं के सम्बन्ध में विश्वस्त आकड़ों की गहरी आवश्यकता महसूस की गयी। तदनुसार व्यवस्थित तथा संगठित रूप से

पशुओं की गणना प्रथम बार १९१९-२० में की गयी और उसके बाद पंच वार्षिक रूप से होती रही।

पहले की गणनाओं की अपेक्षा अप्रैल १९५१ में भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और सांख्यिकी निर्देशालय ने जिस सप्तम पशु-गणना का सगठन किया उसका आधार बेहतर था। अप्रैल १९५६ में हुई आठवीं गणना में और भी सुधार हुआ। इस गणना में घर-घर के हिसाब से परिगणन किया गया, सभी राज्यों ने एकसम आधार पर गणना करनेवालों व व्यवस्थापकीय अधिकारियों द्वारा अपनाये जाने के लिए बुनियादी सिद्धान्त व परिभाषाएँ एवम् स्तरीय निर्देश बनाये, निर्धारित किये गये, विभिन्न कार्यों के लिए एक गणना कैलेंडर निर्धारित किया गया, और यथासम्भव एक निश्चित तारीख—उदाहरणार्थ १५ अप्रैल—के सन्दर्भ में वास्तविक गणना की गयी। गणना के आकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए एक अमूमन नमूने के आधार पर प्राथमिक गणना के विवेकपूर्ण निरीक्षण का सगठन किया गया। अप्रैल १९६१ में हुई नवम् पशु-गणना का सगठन भी उन्नत आधार पर हुआ।

तालिका ४ में प्रस्तुत अन्तिम तीन गणनाओं में एकत्रित आकड़ों से पता चलता है कि किस प्रकार पिछले दस वर्षों में भारत के गोजातीय पशुओं—जिनमें मवेशी व भैंस-भैंसे शामिल हैं—की उच्च अनुपात में वृद्धि हुई है।

सन् १९६१ में समाप्त होनेवाले दस वर्षीय काल में गोजातीय पशुओं की सुस्थिर वृद्धि में १९५६-६१ के दौरान १९५१-५६ की अपेक्षा काफी ऊँची दर से वृद्धि हुई। कुछ अंश में यह बात पशु-गणनाओं के सम्बन्ध में अपनाये गये क्रमिक रूप से उन्नत तौर-तरीकों के कारण विशुद्ध सांख्यिकीय हो सकती है।

मवेशियों के एक अच्छे खासे भाग का खेती के काम में व्यवहार होता है। सन् १९६१ में ७ करोड़ ६० लाख काम में आनेवाले बैल, ७१ लाख भैंसे, ५ करोड़ १० लाख गायें, और २ करोड़ ४२ लाख दुधारू भैंसे थीं। तीन वर्ष तथा उससे ऊपर की उम्रवाले मवेशियों में नर और मादा का अनुपात १३३ १०० था, जबकि (१) भैंसों के सबध में यह अनुपात ३१ १०० था। इस अन्तर का कारण इन दो प्रकार के मवेशियों की तुलनात्मक उपयोगिता में निहित है। खेती के काम में बैल भारी भरकम न होने और चुस्त होने की वजह से सामान्यतः उन्हें तरजीह दी जाती है। देहाती क्षेत्रों में गाय दूध की अपेक्षा बैल-प्राप्ति के लिहाज से अधिक रखी जाती है। इसके विपरीत डेरी काम के लिए गायों की अपेक्षा भैंसों को अच्छा समझा जाता है।

सन् १९६१ में भारत में गोजातीय पशुओं की आबादी में १९५६ से ११४ प्रति शत अधिक वृद्धि हुई। यह वृद्धि अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न रही—जैसे पश्चिम बंगाल में ४३ प्रति शत और उड़ीसा में

तालिका ४

मवेशी और भैंस-भैंसों की सख्या में वृद्धि : १९५१-६१ • (सख्या लाख में)

वर्ष	मवेशी	भैंस-भैंसे	योग	पूर्व गणना से वृद्धि	पूर्व गणना से वृद्धि का प्रातिशत्य
१९५१	१,५५३	४३४	१,९८७	—	—
१९५६	१,५८७	४४९	२,०३६	४९	२५
१९६१	१,७५७	५११	२,२६८	२३२	११४

२५२ प्रति शत। मवेशियों की मर्यादा १०७ प्रति शत बढ़ी और भैंसों की १३९ प्रति शत—मवेशियों (भैंसों को छोड़ कर) की अन्तर्गम्यीय वृद्धि की दर पंजाब में १८ प्रति शत से लेकर उड़ीसा में २४८ प्रति शत हुई और भैंसों के लिए केरल में ६ प्रति शत की गिरावट से उड़ीसा में २९७ प्रति शत की वृद्धि तक—रही। तथापि, यह खुशी की बात है कि तीन वर्षों में ऐसे मवेशियों की मर्यादा में गिरावट आयी है जो न तो किसी काम आते थे और न अभिजनन के लिए ही उपयोगी थे। आर्थिक कारणों से गायों से भी काम लिया जाता है, खास कर वैसे मामलों में जहाँ दूध की प्राप्ति बहुत कम हो। इस प्रकार की गायों की मर्यादा १९६१ में २२ लाख थी, जबकि, १९५६ में १८ लाख। इसी प्रकार भैंसों (मादा) की मर्यादा में भी वृद्धि हुई—१९५६ में उनकी मर्यादा ४ लाख २१ हजार थी और १९६१ में ४ लाख ९८ हजार।

राज्यवार वितरण

सन् १९६१ की गणना के अनुसार राज्यवार वितरण का परीक्षण करते हुए हम देखते हैं कि मवेशियों की सबसे ज्यादा मर्यादा (२ करोड़ ६३ लाख) उत्तर प्रदेश में थी। समग्र देश की मर्यादा का यह १५ प्रति शत है। उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश (१४१ प्रति शत), बिहार (९२ प्रति शत), महाराष्ट्र (८८ प्रति शत), राजस्थान (७५ प्रति शत), मद्रास (६२ प्रति शत), और शेष राज्यों (२५७ प्रति शत) का स्थान आता है। सन् १९५६-६१ की अवधि में तीन वर्षों से ऊपर की आयुवाले मवेशियों की मर्यादा में केरल को छोड़ कर—जहाँ ६ प्रति शत कमी हुई—सभी राज्यों में वृद्धि हुई। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में जवान मवेशियों की मर्यादा में वृद्धि हुई। उक्त राज्यों में कमी का प्रातिशत्य क्रमशः ६७, ७ और २ था।

जहाँ तक भैंस-भैंसों का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश में

उनकी मर्यादा १ करोड़ १० लाख अर्थात् देश की कुल मर्यादा का २१५ प्रति शत थी। आंध्र प्रदेश में उनकी मर्यादा ६९ लाख अथवा १३६ प्रति शत और मध्य प्रदेश में ५६ लाख यानी १०९ प्रति शत थी। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अलावा १९५६-६१ की अवधि में तीन वर्षों से ऊपर के भैंसों की मर्यादा में सभी राज्यों में वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि मद्रास में हुई। इसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा। सन् १९६१ में समाप्त होनेवाली पंच वर्षीय अवधि में केरल और दिल्ली के अतिरिक्त सभी राज्यों की भैंसों की मर्यादा में वृद्धि हुई, सर्वाधिक प्रातिशत्य (६४२) पश्चिम बंगाल का रहा।

गोजातीय पशुओं की सघनता

विभिन्न राज्यों में गोजातीय पशुओं की सापेक्षिक सघनता के अध्ययन से पता चलता है कि बोयी गयी समग्र भूमि के प्रति १०० हेक्टर जमीन के पीछे सबसे अधिक सघनता (२८३) महाराष्ट्र और गुजरात में है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा का स्थान आता है। इन राज्यों में सघनता क्रमशः १७९, २६७, १४१, १८८, और १६२ है। राजस्थान, मैसूर, दिल्ली और पंजाब में इनकी सघनता कम (क्रमशः ९६, ९२, ७४, तथा ६२) थी। प्रति व्यक्ति मवेशी वितरण हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक (प्रति १०० व्यक्ति ९० मवेशी) थी। इसके बाद मध्य प्रदेश (७६), राजस्थान (६५) और उड़ीसा (५६) का स्थान आता है। समग्र देश के लिए मवेशियों की मर्यादा जोती गयी प्रति १०० हेक्टर भूमि पर ११६ और प्रति १०० व्यक्तियों पीछे ४० है।

भैंसों के सम्बन्ध में प्रति १०० हेक्टर सर्वाधिक सघनता (५७ भैंस) आंध्र प्रदेश में है। जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में उनकी मर्यादा क्रमशः ५३, ५०, ५०, ४८,

और ४५ है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इनकी सघनता सबसे कम (क्रमशः १६ और १८) है। प्रति १०० व्यक्ति के लिए राज से भैंसों की सर्वाधिक घनता (२२) पंजाब में है। यह घनता राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में क्रमशः २०, १९, १७, और १५-१५ है। जोती गयी प्रति १०० एकड़ भूमि और प्रति १०० व्यक्ति पीछे अखिल भारतीय घनता ३४ तथा १२ है।

मवेशी और भैंसों में नश्वरता

तालिका ५ में बैलों, गायों, भैंस व भैंसों का १९६१ की गणना (अस्थायी आकड़े) के अनुसार विभिन्न आयु-वर्गों में अखिल भारतीय वितरण दिया गया है,

तालिका ५

भारत में आयु और लिंगानुसार मवेशी व भैंस-भैंसों का वितरण. १९६१

आयु	मवेशी (लाख में)			भैंस-भैंसे (लाख में)		
	बैल	गाय	योग	भैंसे	भैंस	योग
१ वर्ष से कम	११५	११४	२२९	४१	५८	९९
१ से ३ वर्ष	१२३	१३७	२६०	२५	६०	८५
३ वर्ष से ऊपर	७२५	५४३	१२६८	७७	२५०	३२७

एक वर्ष और एक से तीन वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले जवान मवेशियों में नर तथा मादाओं की संख्या प्रायः एक समान है, जिससे प्रकट होता है कि जहाँ तक मवेशियों का सम्बन्ध है जवान मवेशियों में लिंगभेद के अनुसार चयन नहीं होता। यदि कोई मवेशी मरा न हो तो १ से ३ वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले मवेशियों की संख्या १ वर्ष तक के आयु वर्ग में आनेवालों (नर व मादा दोनों) से दुगुनी होनी चाहिए। लेकिन २ से ३ वर्ष तक के आयु वर्ग की संख्या १ वर्ष तक के मवेशियों की संख्या से केवल १ करोड़ ३५ लाख ही अधिक है। इससे पता चलता है कि जवानों में नश्वरता अधिक है। प्रौढ़ायु वर्ग में गायों की संख्या बैलों से करीब एक-चौथाई कम है,

जिससे पता चलता है कि बैलों के पक्ष में एक निश्चित चयन की प्रक्रिया है। इसका फल यह होता है कि उनकी अधिक अवहेलना होती है और फलस्वरूप मृत्योनुपात भी अधिक है।

निम्न तालिका के कालम ५ और ६ की तुलना करने पर भैंस व भैंसों के सम्बन्ध में एक भिन्न ही रुख सामने आता है। भैंसों के १ वर्ष तक और १ से ३ वर्ष तक के आयु वर्ग की सापेक्षिक संख्याएँ मवेशियों के नर तथा मादा दोनों के ही समान हैं। इससे प्रकट होता है कि जवान भैंसे भी उसी अनुपात में मरती हैं जिस अनुपात में मवेशी वर्ग के जवान नर व मादाएँ। लेकिन भैंसों (मादा) में

नश्वरता बहुत अधिक है, जैसे कि १ से ३ वर्ष तक के आयु वर्ग में भैंसों की संख्या १ वर्ष तक के आयु वर्गवाले भैंसे की संख्या के आधे से कुछ ही अधिक है। जवान तथा प्रौढ़ दोनों ही आयु वर्गों में भैंसों (मादा) की संख्या भैंसों (नर) से अधिक है, प्रौढ़ आयु वर्ग (तीन वर्ष से ऊपर) में यह अन्तर बहुत अधिक है। इसका निश्चित कारण यह है कि चयन की प्रक्रिया जवानी की अवस्था से ही भैंसों (नर) के विरुद्ध है, क्योंकि खीचन शक्ति के लिए उनका विशेष उपयोग नहीं होता।

चूँकि हमारी खेतिहर अर्थ-व्यवस्था में इतने अधिक मवेशी और भैंस-भैंसे नहीं चाहिए अतएव जो भी कम उपयोगी होता है, चयन की प्रक्रिया उसके विपक्ष में काम करती है। इसका परिणाम निकलता है, अधिक

मृत्यु और उसके फलस्वरूप उपयोगी श्रेणियों में एक सीमा तक उनकी मर्यादा बनाये रखने के लिए अधिक पैदाइश को प्रेरणा मिलनी है। इस प्रकार यह दुष्प्रक्रिया चलना रहता है। मवेशी-पालन के सम्बन्ध में एक विवेकशील नीति यह होगी कि नर पशुओं तथा अप-व्ययी गायों का बधीकरण करके जन्मानुपात कम किया जाय एवम् इस तरह जो पशु पैदा हों उनकी सार-सम्भाल अच्छी की जाय ताकि मृत्यु कम हो और इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था को होनेवाला नुकसान कम किया जाय। केवल आवश्यक मर्यादा में ही साइ रखे जाय तथा शेष का बधीकरण कर दिया जाय, और मौजूदा गायों व बैलों की नस्लों में अच्छी नस्ल के माडों के जरिये प्राकृतिक एवम् अप्राकृतिक चयन के जरिये सुधार किया जाय।

अलाभशायक गायों की समस्या

भारत में दो मुख्य उद्देश्यों को लेकर मवेशी रखे जाते हैं (१) दूध प्राप्ति, और (२) कृषि कार्यों के लिए खीचन शक्ति की पूर्ति। जहाँ गाय दूध प्राप्ति व हल खीचनेवाले मवेशी दोनों के रूप में रखी जाती है वहाँ भैंस मुख्यतः दूध प्राप्ति के लिए ही रखी जाती है। भैंस दूध अधिक देती है, लेकिन गाय दूध देने के आलावा ९० प्रति शत से भी अधिक काम के पशु के रूप में काम देती है। कुछ राज्यों में तो बैलों से ही सब प्रकार का काम लिया जाता है। इस प्रकार दूध और खीचने-ढोने के काम के सम्मिलित आधार पर राष्ट्रीय आय में गाय, भैंस से अधिक योगदान देती है। किन्तु गाय का दुग्धोत्पादन इतना कम होता है कि यद्यपि उनकी संख्या भैंसों की दुगुनी से भी अधिक है, उनका दूध भैंसों के दूध के उत्पादन से भी कम है।

भारत में प्रति गाय दूध उत्पादन (१७३ किलोग्राम प्रति वर्ष) भैंस के दूध-उत्पादन (५०७ किलोग्राम प्रति वर्ष) का अमूमन तौर पर एक-तिहाई है। किन्तु जहाँ तक खीचन शक्ति का सम्बन्ध है, चावल उत्पादक क्षेत्रों को छोड़ कर—जहाँ कि पानी में काम करने के लिए भैंसों की उपयुक्तता के कारण उनका काफी हद

तक उपयोग होता है—बैल भैंसों की अपेक्षा अधिक कामिल पशु समझा जाता है। इस तरह भारत में दो प्रकार—काम के लिए बैल और दूध के लिए भैंस—के गोजानीय पशु पाले जाते हैं, जिससे हमारे सीमित साधन स्रोतों पर भारी बोझ पड़ता है। अन्य देशों में—खास कर अधिक प्रगतिशील देशों में—कोई भी दूसरा पशु दूध देने में गाय की बराबरी नहीं कर सकता, जोकि खीचन शक्ति का स्रोत भी है। यह भारत में ही है कि भैंसे अधिक दूध देनी है। चूँकि दूध प्राप्ति और खीचन शक्ति के लिए अलग-अलग विनियोजन के कारण हमारे सीमित साधन-स्रोतों पर अधिक बोझ पड़ता है, इसलिए, किसी प्रकार को अपनाने की शक्यता पर विचार करना वाछनीय होगा जोकि वर्तमान व्यवस्था में कोई विशेष गड़बड़ी पैदा किये बिना धीरे-धीरे क्रमिक रूप से अपनायी जा सकती हो।

अनेक राज्यों में भैंसों में अधिक मवेशी है, जो सम्भवतः इस बात का सकेत करते हैं कि प्रारम्भिक समय में मवेशियों से दूध प्राप्ति और खीचन शक्ति के स्रोत के रूप में काम लिया जाता था। किन्तु देश के अनेक भागों में ऐसा लगता है कि भैंस ने अधिक दूध देने और उसके दूध में घी तथा मक्खन तत्व अधिक होने की वजह से धीरे-धीरे गाय की तुलना में तरजीह प्राप्त कर ली, और उनकी संख्या गायों की अपेक्षा द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए पंजाब में प्रति १०० गायों पीछे १९५१ में भैंसों की संख्या ११४, १९५६ में १२१, और १९६१ में १३७ थी।

भारत में खेती-बाड़ी व अन्य कार्यों में काम आने-वाले पशुओं में करीब ८७ प्रति शत बैल, ९ प्रति शत भैंसे, ३ प्रति शत गाय, और १ प्रति शत भैंसें हैं। इस प्रकार काम देनेवाले पशुओं में मवेशियों का हिस्सा करीब ९० प्रति शत है। नर पशुओं के आधार पर भी अनुपात कोई विशेष भिन्न नहीं है—९१ प्रति शत बैल और ९ प्रति शत भैंसे हैं। मौजूदा

भैंसे काम देनेवाले पशुओं में इतने कम हैं कि इनके स्थान पर बैलों से ही काम लेने की बात पर विचार करना अच्छा होगा। यहाँ तक कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल के चावल उत्पादक क्षेत्रों में भी—जहाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा भैंसों से काफी अधिक काम लिया जाता है—उनका अनुपात काम में आनेवाले कुल पशुओं में केवल ८ से २३ प्रति शत ही है। ऐसी अवस्था में यदि सब-का-सब काम भी बैलों से ही लिया जाय तो भैंसे रखने से छुटकारा पाया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि क्या गायें भी दूध उत्पादन के मामले में भैंसों का स्थान ले सकती हैं? भारत में अमूमन तौर पर प्रति गाय पीछे १३ बैल है। अनेक राज्यों में अनुपात इससे कम है, जबकि कुछ में ही १५ से अधिक है। इस प्रकार यह अनुपात किसी भी राज्य में इतना नहीं है कि वह गायों की सामान्य वहन-क्षमता से अधिक हो अथवा उनकी दूध देने की क्षमता में कमी करे। इसके दूसरी ओर गायों की इतनी बड़ी सख्या न तो मौजूदा बैल शक्ति और न ही मौजूदा दूध उत्पादन बनाये रखने के लिए आवश्यक है। फिलहाल प्रति गाय कम दूध उत्पादन स्पष्टतः ठाठ गायों की सख्या अधिक होने की वजह से है। दुधारू और ठाठ गायों की कुल सख्या में केवल असम और पंजाब ही ऐसे राज्य हैं जिन्हें दुधारू गायों की सख्या अधिक होने का लाभ प्राप्त है, बिहार और मध्य प्रदेश में इनकी सख्या प्रायः समान है, तथा शेष राज्यों में ठाठ गायों की सख्या अधिक है। कुछ राज्यों में ठाठ गायों की सख्या दुधारू गायों की सख्या के १५ गुने से भी अधिक है। समूचे भारत में ठाठी गायों की सख्या दुधारू गायों की सख्या से १३५ गुनी अधिक है। तालिका ६ दुधारू तथा ठाठी गायों की सख्या और प्रति दुधारू गाय दूध-उत्पादन एवम् दुधारू और ठाठ गायों के सम्मिलित रूप से प्रति गाय औसत दूध-उत्पादन के सम्बन्ध में आकड़े प्रस्तुत करती है।

जब कुल दूध उत्पादन में ठाठ और दुधारू गायों का भाग देकर परम्परागत तरीके के अनुसार औसत निकाला जाय तो ठाठ गायों की अधिकता का स्वाभाविक परिणाम है न्यून औसत प्राप्ति। किन्तु इस औसत से गायों के वास्तविक दुग्धोत्पादन व उनकी क्षमता का प्रतिबिम्ब प्राप्त नहीं होता। तालिका ६ से पता चलेगा कि जब हम केवल दुधारू गायों को ही हिसाब में शामिल करें तो प्रति गाय औसत उत्पादन काफी बढ़ जाता है। ऐसे अधिकांश देशों में जहाँ डेरी उद्योग काफी विकसित हो चुका है, दुधारू पशुओं की सख्या ठाठी से अधिक होती है और बुनियादी अर्थ-व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए ठाठ पशुओं की सख्या को नियंत्रित रखा जाता है।

फार्म और मवेशी

फार्म मैनेजमेंट के सम्बन्ध में जो अध्ययन किये गये हैं उनसे प्राप्त आकड़ों से पता चलता है कि फार्मों में जितने पशु हैं उनका दो-तिहाई हिस्सा खीचन शक्ति का काम देनेवाले पशु हैं और शेष दुधारू तथा अन्य प्रकार के मवेशी प्रायः बराबर-बराबर की सख्या में हैं। खीचन-शक्ति-स्रोत के रूप में बैलों की ज्यादा कीमत है और इसलिए उनकी खुराक अच्छी होती है। गायें मुख्य रूप से बछड़े पैदा करने के लिए रखी जाती हैं और अधिकांश फार्मों में दूध-प्राप्ति तो एक अनुप्रासगिक बात है।

इन अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि औसत आकार के दो-तिहाई तक के आकार के खेत अमूमन तौर पर कुल फार्मों के दो-पंचमाश है, किन्तु फार्मों में वे कुल मवेशियों का एक-चतुर्थांश ही रखते हैं। जितने मवेशी वे रखते हैं वे उनकी खुद की सख्या की तुलना में आनुपातिक दृष्टि से काफी कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि मवेशी रखने के लिए उनके पास साधन-स्रोत बहुत सीमित हैं, फार्मों में अधिकांश मवेशी वे व्यक्ति रखते हैं जिनके फार्म औसत आकार के दो-तिहाई से बड़े हैं। तथापि, जहाँ तक खीचन शक्ति का काम देनेवाले मवेशियों का

तालिका ६

दुधारू और ठाठ गायें, उनका प्रातिशत्य तथा प्रति गाय दुग्धोत्पादन १९५६

राज्य	ब्यानेवाली अर्थात् तीन वर्ष से ऊपर की, अभिजनन और दूध के लिए रखी गयी गायें			लब्धि (ठाठ और दुधारू गायें)	प्रति गाय वार्षिक दुग्धोत्पादन (किलोग्राम में)	
	ह. जा. र. में	गैर दुधारू (ठाठ व त्रिनाव्यायी)	योग		दुधारू	कुल
आंध्र प्रदेश	१,४३१	२,०७१	३,५०२	१४५	५१५	२१०
असम	९३१	५७७	१५०८	०६२	१०७	६६
बिहार	१,७९३	२,०७४	३,८६७	११६	६६५	३०८
बम्बई	२,५६०	३,३६०	५,९२०	१३१	२२२	९६
जम्मू और कश्मीर	२३१	०७५	६०६	१६२	३४१	१३०
केरल	३९६	५७५	९७१	१४५	४१९	१७१
मध्य प्रदेश	३,०४५	४,००६	७,०५१	१३२	१७६	७६
मद्रास	१,१६२	१,५५८	२,७२०	१३४	४७३	२०२
मेसूर	१,१८३	१,७२५	२,९०८	१४६	२३९	९७
उड़ीसा	६२७	१,७१४	२,३४१	२७३	३६२	९७
पंजाब	९७६	६५८	१,६३४	०६७	७७७	४६५
राजस्थान	१,७४९	२,६२३	४,३७२	१५०	३६५	१४६
उत्तर प्रदेश	२,३७५	३,३८७	५,७६२	१४३	७१०	२९२
पश्चिम बंगाल	१,३६१	२,१५५	३,५१६	१५८	४३९	१७०
केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	२७५	२९५	५७०	१०७	२६९	१३०
अखिल भारतीय	२०,०९५	२७,१५३	४७,२४८	१३५	४०७	१७३

स्रोत काकम २,१ और ४ के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ इकनॉमिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स खाद्य और कृषि मंत्रालय, कालम ७ के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एण्ड इन्सपेक्शन।

सबध है, कृषक इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से कैसे और कितने मवेशी रखना लाभप्रद होगा। सामान्यतः अपनी जमीन जोतने के लिए वे आवश्यकता से अधिक मवेशी नहीं रखते। फिर भी, फार्मिंग में काम का पैमाना खीचन शक्ति के लिए मवेशी रखने में मितव्ययिता बरतने की गुंजाइश सीमित कर देता है। एक बड़ा किसान एक जोड़ी बैलो से ही छोटे कृषक की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की जोताई कर लेता है। यदि छोटे किसान अपनी आवश्यकताएँ एक साथ मिला कर प्रयोग करे तो उन्हें

कम खीचन शक्ति की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि जब तक फार्मों का आकार बड़ा नहीं होता है खीचन शक्ति का काम देनेवाले मवेशियों की संख्या कम करने की बात शायद ही सोची जा सके, इसलिए इस बात की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है कि बड़े किसान ज्यादा मवेशी रखें।

भावी कार्य

इस प्रकार भारत में प्रमुख सवाल यह है कि ठाठ तथा बेकार गायों व अन्य मवेशियों और दुधारू गायों

तथा अन्य उपयोगी मवेशियों के बीच उपयुक्त सन्तुलन स्थापित किया जाय। कुछ राज्यों में जहाँ दुधारू और ठाठ गायों का अनुपात सगत है, किसी हद तक यह सन्तुलन है, लेकिन अन्य राज्यों में असन्तुलन के अनुसार उनमें बेहतर साम्य मूलक संयोजन स्थापित करने की कोशिश अवश्य ही की जानी चाहिए। यदि न्याय सगत रूप से ऐसा किया गया तो उसका मौजूदा दुग्धोत्पादन पर किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़नेवाला है, बल्कि यह कि मवेशियों की सार-सम्भाल पर कम खर्च होगा और फलस्वरूप दूध उत्पादन की लागत भी कम होगी। काम आनेवाले बैल की पूर्ति पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, गायों की संख्या में कमी करने से शेष के लिए अधिक चारा उपलब्ध होगा, और अच्छी खुराक के कारण गायें जल्दी गाभिन होगी तथा दूध देना बन्द करने व व्याने के बीच का समय कम होगा और इस प्रकार वे अनुक्रमिक रूप से वृद्धि-शील दर पर बछड़े व दूध दोनों ही दे सकेंगी।

बधिया करने व वन्ध्यकरण के जरिये अन्वाधुन्य रूप से बढ़नेवाली संख्या को रोक कर अलाभदायक गायों तथा अन्य बेकार मवेशियों की संख्या कम की जा सकती है। जो गायें रखी जायेंगी उनकी दुग्ध-क्षमता में इन उपायों को काम में लाते हुए सुधार भी किया जायेगा। गायों को प्रमाणित साडों से गाभिन करवाना, भोगान्तर काल कम करना, गायों और बैलों को एक साथ रखने पर परिपूर्ण रोक लगा कर सम्भोग-नियन्त्रण, गायों की नस्ल (नस्ल परीक्षण) के आधार पर साडों को दागना, व्यापक रूप से कृत्रिम सेचन, वैज्ञानिक ढंग में अभिजनन करके इस प्रकार की जननिक विशेषताओं का विकास करना जो कि दूध-उत्पादन व काम में आनेवाले पशु पैदा करने की क्षमता की चरम सीमा व जीव्यता को एक साथ मिला दे, और अधिक तथा अच्छी बुगक की व्यवस्था, मवेशियों की नस्ल सुधारने और रोगों पर काबू पाने के लिए प्रावित्रिक योजनाओं के अनिरिक्त देहाती में ईधन की कमी दूर करने के लिए ईधन वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अन्य उपायों के साथ-साथ किसी प्रकार के फसल आयोजन के अन्दर रहते हुए चारे की खेती का विस्तार करने के लिए समग्र कार्यक्रम बनाने, चलाने पड़ेगे। इस प्रकार हमारी अर्थ-व्यवस्था में मवेशी विकास का उगम कृषि और ग्रामीण विकास

के लिए हमारे जो प्रयत्न हैं उनके आ स्वरूप बनाना, अपना पड़ेगा।

योजना के अन्तर्गत गाय की नस्ल सुधारने और उसकी दूध देने की क्षमता में वृद्धि करने तथा दूध न देने की अवधि में कमी करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। डेरी सत्रों, मिल्क कालोनी तथा अन्य प्रकार की दूध सम्बन्धी योजनाओं से दूध के लिए विस्तृत बाजार प्राप्त होता है और अच्छी नस्ल की एवम् ज्यादा दूध देनेवाली गायें रखने के लिए पशु-पालकों को एक प्रकार की उत्प्रेरणा मिलती है। पर्याप्त और विश्वस्त आकड़ों के अभाव में मवेशी व डेरी विकास के लिए कार्यक्रम बनाने तथा मूल्यांकन करने में अडचन आती है अर्थात् इनका अभाव उक्त काम करने के लिए एक प्रकार की कमी है। इन कामों के लिए प्रमुख गोजातीय मवेशियों की संख्या के सम्बन्ध में फिलहाल जो पंच वर्षीय रूप से जानकारी मिलती है, उससे कुछ जल्दी मिलनी चाहिए।

मवेशियों की क्षमता में सुधार करने हेतु योजना बनाने के लिए मवेशियों की विभिन्न नस्लों तथा उनकी क्षमता और अनेक पशु-उत्पादनों एवम् पशु-पालन पद्धतियों के सम्बन्ध में भी विश्वस्त आकड़ों की अत्यधिक आवश्यकता है। पशु-धन सम्बन्धी आकड़ों के मामले में इन कमियों को दूर करने में नमूना सर्वेक्षणों का बहुत बड़ा महत्व है। इस बात का अध्ययन करने की आवश्यकता है कि विभिन्न दूध योजनाओं से हानि-लाभ क्या है और ग्रामीण सग्रह केन्द्रों पर पशु पालने की पद्धतियों में परिवर्तन तथा पशु-पालकों की आर्थिक अवस्था के सन्दर्भ में उनका क्या प्रभाव पड़ा है। मवेशी विकास कार्यक्रमों की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में ऐसे अध्ययन करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के पशु-पालन और डेरी विकास विभागों में सांख्यिकीय इकाइयों की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। आशा है चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में पशु-पालन विकास कार्यक्रमों के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए परमावश्यक आकड़े इकट्ठे करने सम्बन्धी योजनाओं पर भी उपयुक्त ध्यान दिया जायेगा।

नयी दिल्ली १२ दिसम्बर १९६१

आय वितरण पर एक दृष्टि

विद्या सागर महाजन

विकासोन्मुख देशों का विकास उस दर से— जिस पर कि क्रय-शक्ति के विस्तार से स्थानीय बाजार का निर्माण किया जाता है— वैसे ही निकटतम रूप में सम्बन्धित है जिस प्रकार कि निरन्तर विकास उपभोग में वृद्धि से निकट रूप में सम्बन्धित है और उस पर निर्भर है।

आय वितरण का मामला पूँजीवादी विभाग के अनुकूल होने का मुख्य कारण यह है कि यह विभाग बचत और निवेश के प्रति सचेत है। इस विभाग में जितनी अधिक आय होगी, समुदाय की पूँजी और वृद्धि दर भी उतनी ही बढ़ेगी। अवस्था इसके विपरीत होगी यदि आय मजदूरी करनेवालों जैसे गैर-पूँजीवादियों की जेब में चली जाय, जिनकी उपभोग प्रवृत्ति उच्च है और जिस कारण ही सामुदायिक बचत नहीं हो पाती। फलतः तीव्र विकास के लिए पूँजीवादी विभाग का भी साथ ही साथ-विकास होना चाहिए अथवा अर्थशास्त्रीय भाषा में यह कह सकते हैं कि 'थोड़े-से क्षेत्र में आय बढ़ाने को प्रोत्साहन देने तथा यथा संभव आय को अधिक लोगों में वितरित न होने देने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है।'

विदेशी बाजार पर निर्भरता

उपर्युक्त तर्कों के समर्थन में जबकि प्रायः ऐतिहासिक उदाहरण दिये जाते हैं, इस बात को अच्छी तरह नहीं समझा जाता है कि अभी जो विकसित देश हैं उनमें उनके विकास करने के वक्त जो अवस्था थी, वह आज के विकासशील अर्थात् विकासोन्मुख देशों की अवस्था से मूलतः भिन्न थी। ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण लीजिए। ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था में जबकि तेजी से वृद्धि हो रही थी और उसके साथ ही साथ पूँजीवादी विभाग में आय का वितरण बड़ी उदारता से हो रहा था, यह सुझाना गलत नहीं होगा कि यदि ब्रिटेन

की विदेशी बाजारों तक पहुँच नहीं होती तो यह सम्भव नहीं होता। उसके वस्त्रोद्योग की सफलता, जिसने उसके सम्पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया, बहुत कुछ विदेशी बाजारों के कारण ही थी, भारत जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अतः ब्रिटेन के लिए अपने उत्पादनों के लिए पर्याप्त स्थानीय बाजार का न होना कोई खाम महत्व नहीं रखता था। यह इस बात का भी सुझाव देता है कि यदि किसी अर्थ-व्यवस्था की अपने निर्माताओं के लिए विदेशी बाजार तक पहुँच है तो वह बड़ी तीव्र गति से विकास कर सकती है, जिसमें आय का वितरण पूँजीवादी विभाग में होगा।

दुर्भाग्यवश १९५१-७५ की इस अवधि में यह अब संभव नहीं है। जबकि ब्रिटेन (अथवा जापान) की विकास प्रक्रिया अपने वस्त्र को दूसरे देशों में निर्यात कर आरम्भ हो सकी, नये विकासशील देशों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपना वस्त्र अपने ही देश में बेचना पड़ता है।

विदेशी बाजारों से घरेलू बाजार में स्थानान्तरण का अर्थ यह भी नहीं लगाना चाहिए कि सभी देशों में पर्याप्त घरेलू बाजार ('अथवा आबादी') नहीं है, जोकि उनके उत्पादन को खपा सके। वेस्ट इंडीज, पश्चिम अफ्रीका, आदि जैसे छोटे और विकासोन्मुख देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ घरेलू बाजार इतना छोटा है कि वह अधिकांश निर्माता उद्योगों को जीवित नहीं रख सकता। परन्तु यहाँ भी विकास प्रक्रिया में गतिशीलता

मुख्यतः उनके द्वारा पड़ोसी देशों से मिल कर, जोकि कमोबेश विकास की समान अवस्था में ही हों, सीमा-कर सघ (कस्टम्स यूनियन) बनाने से ही आयेगी।^१

घरेलू क्रय शक्ति

इस प्रकार विकास-समस्या उस गति से निकटतम रूप में सम्बन्धित है, जिसमें विकासशील देश अपनी घरेलू क्रय शक्ति निर्मित करने की योग्यता रखते हैं। पूँजीवादी विभाग की सफलता भी देश के लोगों की क्रय शक्ति पर निर्भर करेगी। अन्य दृष्टि से देखने पर यह सुझाना सही है कि विकासोन्मुख देशों की धीमी प्रगति का एक मुख्य कारण यह है कि उनमें किसी प्रकार जीवन-यापन भर करनेवाले किसानों का बाहुल्य है, जिनकी क्रय शक्ति बहुत ही कमजोर है। अन्ततः यह समस्या गुजर-बसर भर करनेवाले बृहत् विभाग और सीमित आधुनिक औद्योगिक विभाग के बीच के अन्तर को कम करने की हाँ जाती है।

इसी दृष्टि से आय वितरण के प्रश्न पर विचार करना है। निर्धन पूँजीवादी विभाग के हाथों में धन का सकेन्द्रण होने से ही वर्तमान बाजार के गतिरोधों को दूर करने में कोई अधिक सहायता नहीं मिलेगी, जब तक कि इस धन का उपयोग राष्ट्रीय क्रय शक्ति के विकास के लिए नहीं किया जाना। विकासशील देश में राष्ट्रीय क्रय शक्ति का विकास पूँजीवादी विभाग के कार्यक्षेत्र में बाजार के कड़े नियम, पर्याप्त पूँजी के न होने, भारी निवेश की आवश्यकता, लम्बी निर्माण अवधि आदि के कारण सहज ही नहीं आता। इस प्रकार विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में सरकार को राष्ट्रीय महत्व की पूँजी परिसम्पत्ति का निर्माण करने में, जोकि अन्ततः आय वितरण के आधार को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूपों में विस्तृत करेगी,

१ यह घरेलू क्रय-शक्ति के सम्बन्ध में दिये जानेवाले तर्कों का मजबूत विस्तार भर है, जोकि विकास की समान अवस्था वाले देश एक-दूसरे के स्रोतों को योग्यतम ढंग से विकसित करने का भार लेते हैं तो अधिक कारगर होता है।

बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। उदाहरणार्थ, जब लोग पूँजीगत परियोजनाओं में लगे होते हैं तो, वहाँ आय का प्रत्यक्ष वितरण पारिश्रमिक पानेवालों के पक्ष में होता है। इस आय के खर्च करने से उपभोक्ता उत्पादक सामग्री की माँग निर्मित होती है तथा आय का और भी आगे वितरण होता है। संक्षेप में, एक बार जब किसी कार्य, उदाहरण के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम, के जरिये आय वितरण का प्रवाह आरम्भ हो जाता है, तो अर्थ-व्यवस्था के उन अन्य विभागों पर भी उसका माध्यमिक प्रभाव पड़ता है जहाँ रोजगारी, उत्पादन और पूँजी निर्माण बढ़ जाता है।

फिर, परियोजनाओं का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जा सकता है कि अर्थ-व्यवस्था की वह नियमनिष्ठा टूट जाय जोकि विकास की राह में बाधक है। विकास-शील देश में उच्च आय होने से अनाज की माँग भी अनुपातत अधिक बढ़ेगी, जिसका (आनाज का) उत्पादन रोजगारी में वृद्धि की दर से अधिक गति से बढ़ना चाहिए। फलतः प्रारम्भिक पूँजी निर्माण का अधिकांश भाग सिचाई, नहरों की खुदाई करने, भू-सम्प्राप्ति, बाध-बर्खाई, अच्छे बीज, खाद, उर्वरक आदि के वितरण के रूप में होना है, जोकि खेत का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा।

उपभोग और विकास

अच्छी पौष्टिकता और कार्य-क्षमता के सन्दर्भ में भी भोजन का अनुकूल प्रभाव आर्थिक विकास की दृष्टि से इतना स्पष्ट है कि इससे ताज्जुब ही होता है कि इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। निश्चय ही अधिक विकसित देश भी प्रति कर्मी उत्पादकता बढ़ाने में प्रगति नहीं करते, यदि उनकी श्रमिक शक्ति कम विकसित देशों की तरह पूरी खुराक नहीं पाती। यह इस बात की पुष्टि करता है कि विकासशील देशों में निरन्तर विकास के लिए खपत बढ़ाना महत्वपूर्ण है और कम उपभोग के सिद्धान्तवालों की इस बात का विरोध करता है कि

विकास उपभोग निग्रह से सम्बन्धित हैं।^२

आय वितरण की समस्या को इस नयी दृष्टि से ही समझना होगा। तीव्र विकास के लिए पूंजीवादी विभाग के पक्ष में आय-वितरण का प्रतिष्ठित तर्क विकासशील देश के लिए सिर्फ इसलिए सही नहीं बैठना कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अपना मूल विकास-प्रोत्साहक प्रभाव बहुत-कुछ खो चुका है, जोकि उन्नीसवीं सदी में तथा बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में बहुत अधिक था।^३ अब अर्थ-व्यवस्थाओं को अपने घरेलू बाजार के दल पर विकसित होने को बाध्य किया जाता है। फलतः क्रय शक्ति के विस्तार के जरिये स्थानीय बाजार की वृद्धि विकास के लिए अनिवार्य हो जाती है।^४

भारत में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, वह विकास की उपर्युक्त पद्धति में ठीक बैठता है। भारतीय आयोजक प्रारम्भ में ही यह जानते हैं कि देश के विकासार्थ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अधिक सम्भावना नहीं रखता, भले ही

रसायन, धातु आदि जैसी वस्तुओं के निर्यात के लिए, जिनकी मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती ही जा रही है, बहुत जोरदार प्रयास किया जाय, क्योंकि सुगठित और सुव्यवस्थित अर्थ-व्यवस्थाओं में बड़ी कड़ी प्रयोगिता करनी पड़ती है।

परिणामस्वरूप, वृहत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की सम्भावना और बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। यह दो प्रकार से किया गया है। प्रथम, सामाजिक पूँजी को बढ़ाकर और द्वितीय, देश में अतिरिक्त क्रय शक्ति का निर्माण कर, जिसके लिए सामाजिक पूँजी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप में योगदान दिया है। उदाहरणार्थ, प्रथम और द्वितीय योजनाओं में सार्वजनिक विभाग का अधिकांश निवेश सामाजिक पूँजी के रूप में था। भारत के विकास में यानायात, मिचवाई, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता दी गयी है (तालिका १ देखें)। इन मुविधाओं ने अर्थ-व्यवस्था के

२. तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि अस्वास्थ्यक होने पर भी उपभोग पर कोई रोक नहीं रखनी चाहिए। आखिर जब उपभोग समाज की सामान्य अथवा निर्मित उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाता है तो स्फीति की अवस्था पैदा हो जायगी और विकास दर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि उपयुक्त-राजकोपीय, आर्थिक और प्रशासनिक-उपाय साथ-साथ अपनाये जायें ताकि जरूरत से ज्यादा उपभोग पर रोक लगायी जा सके।

३. यह (सम्पूर्ण) विकासोन्मुखी प्रभाव भी मुख्यतः हाल में बसाये गये क्षेत्रों तक ही सीमित था जैसे उत्तरी अमेरिका, ओसीनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड), जिनमें मुख्यतः वे लोग आ बसे हैं जोकि तंग बसे पश्चिमी यूरोप और इंग्लैंड से निकल आये हैं, और स्वभावतः इनकी संस्कृति पश्चिमी यूरोप जैसी ही है। (इस विषय पर स्वर्गीय प्रो. रागनर नर्कसे (Ragnar Nurkse) का लिखा विस्तृत लेख पैटर्न्स ऑफ़ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन स्टॉक होम, १९५८ में पढ़ें।) जहाँ तक एशिया और अफ्रीका के कम विकसित देशों का सवाल है, प्रो. गुन्नार मिडेलरीक ही सुझाते हैं कि उन्हें महज बचा-बचा ही मिला, जैसे जबकि विदेशी निर्यात गुटो ने स्थानीय प्राथमिक

उत्पादों का निर्यात तथा आयातीन उत्पादक वस्तुओं का वितरण कर बहुत धन इकट्ठा कर लिया, स्थानीय औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र समाप्त हो गये और उनका स्थान किसी अधिक योग्य व्यवस्था ने नहीं लिया—इकनॉमिक डियरी एंड अडर-डेवलपड रेजियन्स।

४. किन्तु यह सुझाना बिल्कुल गलत होगा कि वर्तमान विकासशील देशों के लिए विदेशी व्यापार का कोई खास मूल्य ही नहीं है। यही तथ्य कि विकास अन्य देशों से बड़े-बड़े सयंत्रों और यांत्रिक माध्यमिक वस्तुओं व तकनीकल जानकारी प्राप्त करने की मांग करता है, यह भी बताता है कि इस आयातीन माल की कीमत देने के लिए पर्याप्त निर्यात कार्यक्रम भी होना चाहिए। इस प्रकार भारत जैसे विशाल देश में भी देशी बाजार पर ही पूर्णतः निर्भर करना आर्थिक विकास की दृष्टि से घातक होगा। इससे यह सबक मिलता है कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अब 'विकास का इंजिन' नहीं रहा जैसा कि अधिकांश वर्तमान विकसित देशों के मामले में रहा है, फिर भी वर्तमान अवस्था में इसे देशी बाजार के विकास के साथ प्रभावशाली ढंग से जोड़ देना चाहिए।

लिए उत्पादन और वितरण की आधुनिक पद्धतियों का विस्तृत करने में और भी सहायता मिली है। सिचाई द्वारा खोल दिया है, उद्योगों का प्रसार पिछड़े क्षेत्रों में और अन्य कृषि विस्तार योजनाओं पर किये गये खर्च भी हुआ है और उमने राष्ट्रीय पैमाने पर रोजगारी के से भू-स्तर में सुधार हुआ है तथा उससे भारतीय कृषकों के अवसर निर्मित किये हैं। "स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिली है। फिर, मे सुधार ने मानव पूँजी में सुधार किया है और विकास जिस हद तक उद्योग और सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों में इसे बहुत बड़ा कारक बना दिया है। ने कृषि में लगे अतिरिक्त लोगों के लिए रोजगारी के

तालिका १

सामाजिक बंधा खर्च

(लाख रुपये में)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
यातायात (संचार सहित)	५७,१०० (२४)	१,२९,००० (६९)	१,४५,००० (८६)
सिचाई (छोटी परियोजनाओं को छोड़ कर)	३७,००० (१५४)	४५,००० (९८)	६५,००० (९०)
बिजली	२६,००० (१११)	४१,००० (८९)	९२,००० (१२८)
सामाजिक सेवाएँ	५३,२०० (२२४)	८६,००० (१८७)	१,२५,००० (१७२)
सामुदायिक विकास और सहकार	९,००० (३८)	२१,००० (४६)	४०,००० (५५)
ग्रामीण और लघु उद्योग	४,९०० (२०)	१८,००० (३९)	२५,००० (३४)

टिप्पणी कोष्ठक में दिये गये आँकड़े प्रत्येक योजना में सार्वजनिक विभाग के कुल खर्च के प्रातिशत्य स्वरूप हैं।

लघु और कटौत उद्योगों पर आवश्यक बल तथा अवसर निर्मित किये हैं, उस हद तक ग्रामीण विभाग में उन्हें आवश्यक सहायता (तकनीक, आर्थिक और इनके आय में वितरण हुआ है तथा रोजगारी के अवसर निर्मित ही बड़े उद्योगों के उत्पादनों की जगह इनके उत्पादनों हुए हैं, जिससे किसानों के रहन-सहन और जीवन-स्तर को तरजीह दे कर) देने में आय वितरण के आधार को में सुधार हुआ है।

१. सर्वजनिक विकास के तीनों इस्पात कारखाने उन स्थानों में हैं, जहाँ कि पहले कोई उद्योग नहीं था। इन कारखानों ने उनके निर्माण, स्थापन, रख-रखाव और दैनिक कार्यवाही की प्रक्रियाओं में (बड़े पैमाने पर) रोजगारी के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त आस-पास के स्थानों में नयी औद्योगिक

इकाइयाँ खड़ी करने में मदद दी है, जिन्होंने पहले के पिछड़े इलाकों में रोजगारी के और भी अवसर निर्मित किये हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक विभाग के अन्य उद्योगों तथा निजी विभाग के चन्द उद्योगों ने भी सरकारी औद्योगिक नीति का अनुसरण करके अपने कारखाने लुब्धतात्मक रूप में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये हैं।

दूसरा प्रश्न उठता है इसका असल मासिकीय प्रमाण क्या है? यद्यपि तृतीय पंच वर्षीय योजना में दिये गये आकड़ों का इन्तेमाल करने में मावधानी बरतनी चाहिए, तथापि, ये उपर्युक्त सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं। प्रथम, कृषि उत्पादन ही लीजिए। सन् १९५१ और १९६१ के बीच कृषि उत्पादन ४६ प्रति शत बढ़ा है, जिसने कैलॉरी-पान में १७ प्रति शत वृद्धि की है।^६ कुल वस्त्र उत्पादन में ६२ प्रति शत वृद्धि हुई है, जिसमें खादी, हाथ करघा और शक्ति करघा वस्त्रों के उत्पादन में १६२ प्रति शत वृद्धि हुई है तथा दम वृद्धि ने प्रति व्यक्ति वस्त्रोपभोग १९५०-५१ के ९२ गज से बढ़ा कर १९६०-६१ में १५५ गज कर दिया है (मूल्य वृद्धि के बावजूद)।

पूजीगत सामान और खनिज उद्योगों में तो और भी वृहत् प्रगति हुई है। स्टील इगनाट, मशीनी औजारों और अलुमिनियम के उत्पादन में क्रमशः १५०, १,५१८ और ४०० प्रति शत वृद्धि हुई है। और, ये तो मिर्फ चन्द उद्योगों के ही उदाहरण हैं। जहाँ सन् १९५०-५१ में भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का निर्माण नहीं हुआ करता था, वहाँ १९६०-६१ में इनका उत्पादन-स्तर ५७ लाख टन तक पहुँच गया। कच्चे लोहे के उत्पादन में २३४ प्रति शत वृद्धि हुई, परन्तु कोयले में सिर्फ ६० प्रति शत, पूजीगत सामग्री उद्योगों में दिनादिन सरकार के अधिकाधिक भाग लेने से औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में अच्छी वृद्धि हुई है—दम वर्ष में ये ९४ अंक बढ़ गये हैं।^७

सामाजिक मदों में प्रगति अर्थ-व्यवस्था के अन्य विभागों की प्रगति की तरह ही बनाये रखी गयी है। उदाहरणार्थ, विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता १४८ प्रति शत बढ़

गयी है (यद्यपि इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित दर में नहीं हुआ है), रेलवे द्वारा ढोये गये माल में ६८ प्रति शत वृद्धि हुई है (जोकि रेलवे की वृहत् क्षमता दर्शाती है), सड़कों के क्षेत्र में ४८ प्रति शत वृद्धि हुई है (इनमें से अधिकांश सड़कें अध-पक्की हैं, जोकि सुदूर गाँवा को शहरों से मिलाती हैं) और जहाजरानी की क्षमता १३१ प्रति शत बढ़ी है (यद्यपि यह भारत के व्यापार को देखते हुए बहुत कम है)।

चिकित्सा सुविधाएँ और शिक्षा प्रदान करने में भी इसी प्रकार प्रगति हुई है। डाक्टरों की संख्या २५ प्रति शत बढ़ी है और अस्पतालों में बिछौनों की संख्या ६५ प्रति शत। महामारी और छुआछूत की बीमारियों को रोकने में बहुत अधिक प्रगति हुई है। सन् १९५१ के पूर्व मलेरिया भारत की बहुत बड़ी आबादी के लिए घातक मिद्ध हुआ था, अब वह करीब-करीब मिट ही चुका है। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ८५ प्रति शत बढ़ी है और इंजीनियरिंग तथा तकनालाजी की शिक्षा लेनेवालों की संख्या २३९ प्रति शत।

निर्यात पीछे रहा है, यह तो इसी से मिद्ध है कि इन १० वर्षों में मिर्फ ३ प्रति शत वृद्धि हुई है। अतः विदेशी अनुव्रधों को पूर्ण करने के लिए हमें अब से कहीं अधिक ध्यान निर्यात व्यापार पर देना है।

आय में असमानता

भारत ने निश्चय ही इस दशक में उत्साहजनक प्रगति की है। यह पूछा जा सकता है कि इस प्रगति ने समाज के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से वास्तव में कितना लाभ पहुँचाया है। उदाहरणार्थ, आम तौर पर यह शिकायत

६. यही बड़ी उत्साहजनक बात है कि जहाँ प्रति व्यक्ति चावल, ज्वार और अन्य अनाजों के उपभोग में नाम मात्र की वृद्धि हुई है तथा कुछ मोटे अनाजों में तो कमी ही हुई है, गेहूँ की प्रति व्यक्ति खपत करीब ४९ प्रति शत बढ़ी है।

७. सूचकांक में असल वृद्धि अधिक लगती है। यह इस कारण है कि जिस सामग्री को शामिल किया गया है उसकी गणना पुराने वजन के आधार पर की गयी है। जैसा कि पिछले

दशक में इस्पात, रसायन और सामान्य इंजीनियरिंग जैसे नये उद्योगों ने परम्परागत उद्योगों (जैसे वस्त्र) से कहीं अधिक गति से प्रगति की है, नये वजन के अनुसार सूचकांक में संशोधन करने से सम्पूर्ण औद्योगिक विकास में वृद्धि का उच्च प्रातिश्लय प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में देखिए डाक्टर वी० के० आर० वी० राव का लेख. भारत में औद्योगिक क्रांति—खादी ग्रामोद्योग के जून १९६३ के अंक में प्रकाशित।

की जाती है कि हाल के औद्योगीकरण ने समाज में आय की असमानता को कम करने के बदले और भी बढ़ा दिया है। इस वक्तव्य में कितना तथ्य है? उपर्युक्त कथन को सही या गलत बनाने के लिए सांख्यिकी सामग्री की बहुत कमी है (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किये गये चन्द सर्वेक्षणों को छोड़ कर, जोकि आद्यतन नहीं है)। आय जाँच समिति उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने में कहाँ तक सफल हुई है, यह देखना अभी बाकी है। अतः हमें समस्या की तह तक पहुँचने के लिए कोई व्यापक तरीका अपनाना चाहिए।

आय के सकेन्द्रण के सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं (अ) इस आय के पानेवाले कौन हैं, और (आ) वे इसका उपभोग कैसे करते हैं?

अ दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिनके हाथ में धन है। प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सार्वजनिक विभाग, जहाँ धन का सकेन्द्रण सन् १९६१ से योजित विकास काल शुरू होने के बाद से काफी ऊँची दर से बढ़ा है। इसका एक प्रत्यक्ष मार्ग है सरकारी (केन्द्रीय और राज्य यानी दोनों सरकारें) राजस्व में तीव्र गति से वृद्धि, जोकि १९५०-५१ के ७ अरब ८१ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९६०-६१ में १७ अरब ७६ करोड़ १० लाख रुपये हो गया है। यदि हम इसमें पूँजीगत प्राप्ति जोड़े—जोकि इसी अवधि में १ अरब २५ करोड़ से बढ़ कर १७ अरब ७६ करोड़ १० लाख रुपये हो गयी है—तो सरकार के हाथ में धन (आय) का सकेन्द्रण काफी अधिक हुआ है। पिछली दो योजनाओं में सार्वजनिक विभाग के निवेश कार्यक्रमों को देखने से भी इस धन सकेन्द्रण की पुष्टि होती है, जोकि दूसरी योजना

में पहली योजना के देने से भी अधिक ३ अरब ६५ करोड़ रुपये था अर्थात् १९६०-६१ की राष्ट्रीय आय का एक-चौथाई था।

धन पर अधिकार रखनेवाला दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है निजी (औद्योगिक) विभाग, जोकि कम से कम सार्वजनिक विभाग जितनी ही गति से बढ़ा है—निगम क्षेत्र में इन दस वर्षों से प्रदत्त पूँजी करीब २५० प्रति शत बढ़ी है।^८ अधिक महत्वपूर्ण इस विभाग की आर्थिक गति-विधियों में आयी बड़ी विविधता है, जिसमें पूँजीगत सामग्री उद्योगों का महत्वपूर्ण गति से विस्तार हुआ है।^९

दूसरी ओर, भूस्वामियों और राज-रजवाडों के शासकों के हाथ जो धन सकेन्द्रण हुआ था, उसमें काफी कमी हुई है। इनमें बहुत लोग पूँजीवादी विभाग की ओर चले गये प्रतीत होते हैं और उस हद तक अर्थ-व्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की दृष्टि से पूँजीवादी विभाग का यह तीव्र विकास और सामान्त विभाग का हास बढ़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि निवेश और बचत करनेवाले वर्गों के सघटकों में एक निश्चित परिवर्तन है—अब ये सघटक जमींदारी और राज-रजवाडे न हो कर सरकार तथा निजी औद्योगिक विभाग से सम्बद्ध वर्ग हैं। इसने खर्च पद्धति को भी बदल दिया है। अब पहले की तरह विलासिता की वस्तुओं के बजाय आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। जबकि पहले जमींदार और राजा-महाराजा अपने धन

८. जबकि १९५१ और १९६० के बीच निजी निगम विभाग में प्रदत्त पूँजी २ अरब ८९ करोड़ रुपये से बढ़ कर ७ अरब ८९ करोड़ रुपये हो गयी, कम्पनियों की संख्या (१९,९६४ से बढ़ कर १९,६१५) में सिर्फ २० प्रति शत ही वृद्धि हुई सभी ज्वॉइंट स्टॉक कम्पनियों (सार्वजनिक और निजी) में प्रदत्त पूँजी दूनी हो गयी। देखिये, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नयी दिल्ली का मासिक सांख्यिकी विवरण।

९. विभिन्न यात्रिक सामान्य इजीनियरिंग और रसायन उद्योगों का तीव्र विकास—इनमें जितने मदों को शामिल किया गया है उनमें से कई तो १९५१ में निर्मित ही नहीं हुए थे अथवा प्रायोगिक अवस्था में थे—अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन के एक नये बयार का संकेत देता है (सरल उपभोक्ता और इस्के इजीनियरिंग उत्पादनों से सर्वाधिक उल्लेख हुए आधुनिक उत्पादनों की ओर)।

का उपयोग सोना और हीरे-जवाहरात खरीदने, ऐंगो-आराम, विदेशों की सैर करने आदि में करने थे, अब पूँजीवादी विभाग का अधिकांश धन सत्र, मशीन आदि जैसी जमा पूँजी में लगता है, जोकि उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत करता है, रोजगारी का क्षेत्र बढ़ाता है।

यद्यपि 'प्रदर्शनात्मक प्रभाव' अभी पहले से अधिक प्रचलित है, तथापि 'प्रदर्शनात्मक प्रभाव' शब्द का इस्तेमाल करने में भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह का प्रदर्शन सचमुच विकास का एक अभिन्न अंग है जो कि प्रक्रिया को गति देता है। उदाहरणार्थ, तथाकथित 'यू' विभाग द्वारा पश्चिमी उपभोग पद्धति की नकल तथा इस विभाग की उपभोग पद्धति की अन्य आय-वर्गों द्वारा नकल-ने बहुत-से नये उद्योगों को खड़ा करने में मदद दी है। प्रदर्शनात्मक प्रभाव—जैसा कि यह पहले था—मुख्यतः बहुत ही थोड़ी माँग की विलासिता-सामग्री तक ही सीमित है और औद्योगीकरण तथा रोजगारी पर उसका प्रभाव नगण्य-सा है।

आ सार्वजनिक विभाग की तीव्र प्रगति रोजगारी के अवसर बढ़ाने के साथ निकटतम रूप से सम्बन्धित है, जिसे हमारे आयोजन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। निष्क्रिय और अर्ध-सक्रिय जन-स्रोतों में छिपे धन का पूर्ण एहसास कर उत्पादन की उन तकनीकों को प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान दिया गया है जोकि इनका अधिकतम उपयोग करते हैं। विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों में श्रम-प्रधान पद्धतियों का उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में आकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि अभी विभिन्न निर्माण योजनाओं में कितनी

जन-शक्ति लगी है, और इस आलोच्य अवधि में कितनी जन-शक्ति लगी, इसके भी आकड़े प्राप्त नहीं हैं, जोकि तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी हों। सम्भवतः इस तरह के आकड़े प्राप्त करना सहज नहीं है। कारण कि निर्माण कर्मियों का स्थायी हल नहीं है—इस तरह के कर्मियों को परियोजनाओं की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। यह भी सच है कि निर्माण कार्य के लिए कर्मियों की पूर्ति और उनकी प्रत्यक्ष नियुक्ति में ठेकेदारों का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे कि मामला और उलझ जाता है, क्योंकि वे अपनी बही आद्यतन नहीं रखते। तथापि, योजनाओं की बड़ी सख्या को देखते हुए, जोकि योजनावधि में या तो पूरी हो चुकी है या अब पूरी होनेवाली है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन योजनाओं में रोजगारी पाने-वालों की सख्या काफी बड़ी है।

निजी विभाग में भी रोजगारी की गति काफी तेजी से बढ़ी है, यद्यपि भारतीय कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले कारखानों, खानों और बागानों में उनकी वृद्धि-गति कोई महत्वपूर्ण नहीं है।^{१०} बादवाला सम्भवतः यह दर्शाता है कि सगठित अथवा भारी उद्योग में रोजगारी क्षमता अभी भी बहुत सीमित है।^{११} इसके विपरीत गृह-निर्माण, लघु और कुटीर उद्योगों, वितरण व्यापार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगारी बड़ी तीव्र गति से बढ़ी है।^{१२} लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की सरकारी नीति तथा गृह-निर्माण उद्योग के लिए बहुत अधिक माँग—औद्योगीकरण और शहरीकरण के फलस्वरूप—दोनों ने रोजगारी में वृद्धि करने में बहुत मदद की है।

१०

रोजगारी	१९५०	१९५१	१९५०
अ. कारखाने में	२,९५९	३,११४	३,४०६
आ खानों में	५४४	५९२	६१८
इ. बागानों में	१,२६९	१,१३६	१,२५८(१९५८)
(अक हजार में हैं)			

११ यह पक दिलचस्प बात है कि जबकि १९५१ से १९५० के

बीच कारखाना उद्योग में रोजगारी में २२ प्रति शत से कम वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में उनका योगदान १४४ प्रति शत रहा, जोकि बहुत बड़ी आय का संकेत कराता है—बड़े उद्योगों की प्रोत्साहक क्षमता दर्शाता है।

१२. रोजगारी सम्बन्धी आंकड़े सिर्फ व्यापारिक संस्थाओं के ही उपलब्ध हैं, जिनमें १९५० और १९५९ के बीच अढ़ाई गुनी वृद्धि हुई।

इस प्रकार उपर्युक्त सर्वेक्षण से, यद्यपि वह अधूरा है, मुख्य निष्कर्ष यही निकलता है कि आय के वितरण में विस्तार और सकेन्द्रण साथ-साथ हुआ है, न कि सिर्फ सकेन्द्रण, जैसा कि अधिकतर दावा किया जाता है। सार्वजनिक और निजी विभाग में धन के सकेन्द्रण के साथ-साथ ही आय वितरण प्रक्रिया भी विस्तृत हुई है। ये दोनों निकटतम रूप से सम्बन्धित रहे हैं और भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विकास निश्चित करनेवाले मुख्य साधन सिद्ध हुए हैं। सरकार और निजी विभाग के हाथों में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण ने समाज के लोगों में आय के अन्तर को बढ़ाने के बदले उसे कम किया है। उदाहरणार्थ, पहले जबकि मध्यम वर्ग के औसत सदस्य और निम्न वर्गों के सदस्यों की आय में बड़ा अन्तर था, अब यह अन्तर कम हो गया है। (तनकीकल कर्मचारियों की स्थिति

तो और भी अच्छी है।) ग्रामीण और शहरी विभाग के बीच का अन्तर भी कम हो रहा है। विभिन्न विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण विभाग की बढ़ती हुई समृद्धि ने औसत किसान को अपनी आय सुधारने में सहायता की है और बदले में आय का उपयोग ग्रामीणों की उपभोक्ता और उत्पादक वस्तुओं दोनों—जैसे साइकिल, सिलाई की मशीन, रेडियो, घड़ियाँ, फाउटेन पेन, जूते आदि—तथा विभिन्न कृषि यंत्रों की मँग बहुत बढ़ाने में किया गया है। इस प्रकार आधुनिक बदलौन अर्थ-व्यवस्था सीमान्तों ने—विकास की हाल की पद्धतियों की दया से—सुदूर गाँवों में भी तेजी से प्रवेश पा लिया है जिससे हमारे विकास में एक नयी शक्ति का निर्माण हुआ है।

कलकत्ता ११ नवम्बर १९६३

औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों में गुजरात भी एक है। अन्दाज है कि १९५५-५६ में ८,७०,०० लोग औद्योगिक कार्यों में लगे थे और उनका योगदान १ अरब १५ करोड़ रुपये का अर्थात् राज्य की आय के एक-पचमांश से कुछ अधिक था। फैक्टरीज एक्ट के अन्तर्गत आनेवाले प्रतिष्ठानों में उद्योगों में रोजगारी पानेवालों में से ४० प्रति शत लोग लगे थे, परन्तु उनका योगदान कुल औद्योगिक उत्पादन के दो-तिहाई से अधिक रहा। राज्य में औद्योगिक विकास की एक प्रमुख विशेषता यह है कि औद्योगिक गतिविधियाँ व्यापक रूप में फैली हुई हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में बटी हुई हैं। प्रमुख औद्योगिक केन्द्र हैं. अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भावनगर, जूनागढ़ और राजकोट।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात: नेशनल
काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

आदिवासियों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर

दत्तात्रेय ना. वान्देकर

परिगणित क्षेत्र और परिगणित जनजाति आयोग ने आदिवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय योजनाओं का उनके जीवन पर कोई खाम प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि इन क्षेत्रों में वन्य उद्योगों को उपयुक्त ढंग से संगठित करें तो उनसे तीन करोड़ आदिवासियों की दयनीय अवस्था में सुधार लाने में बड़ी मदद मिलेगी।

स्वार्दी आयोग के जुलाई १९६३ अंक में श्री वैकुण्ठ

ल मेहता ने अपने लेख 'न्यूनतम जीवन-स्तर की प्राप्ति' में यह दिखाया है कि किस प्रकार ६० प्रति शत लोगों की मासिक आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत आय २५ रुपये से भी कम है। अपने इन भाइयों की गरीबी अथवा दुर्दशा—परिगणित क्षेत्र और परिगणित जन जाति (डेबर) आयोग के शब्दों में—का अन्दाज निम्न तालिका में दिये गये प्रति व्यक्ति आय के आकड़ों से ही लगाया जा सकता है।

नितल श्रेणी के प्रथम दस प्रति शत ७ रुपये से रकम

” द्वितीय ” ”	१० ” ”
” तृतीय ” ”	१२ ” ”
” चतुर्थ ” ”	१५ ” ”
” पंचम ” ”	१८ ” ”
” षष्ठम ” ”	२१५० ” ”

हृदय विदारक अवस्था

ये आकड़े स्थिति को सुस्पष्ट कर देते हैं। पाँच सदस्यवाला एक परिवार, जिसकी औसत मासिक आय ३५ रुपये हो, आज के जमाने में जबकि हर चीज की कीमत इतनी अधिक है, किस प्रकार का जीवन व्यक्तीत कर रहा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जबकि स्वास्थ्य और पौष्टिकता का न्यूनतम स्तर बनाये रखने हेतु अकेले भोजन के लिए ही ३५ रु × ५ = १७५ रु. की आवश्यकता पड़ती है।

जगली इलाको में रहनेवाले आदिवासियों के गरीब से गरीब परिवार से भी मैंने मुलाक़ात की है। हाल ही में मैं बम्बई के सत जेवियर कालेज के विद्यार्थियों के साथ महाराष्ट्र के थाना जिला स्थित कोमबाड के निकट बराईपडा गया था। वहाँ गहली ही झोपड़ी में हमें स्थानीय लोगों की हृदय विदारक अवस्था देखने को मिली। कालेज की छात्राओं ने झोपड़ी के दरवाजे को खोला तो नजर आया कि एक वृद्धा एक गंदे चिथड़े में कुछ बाघे मचान की सीढियों से उतर रही है। हमने जानना चाहा कि वह क्या कर रही है। उसने बताया कि बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं और घर में कुछ खाने को नहीं है, अतः वह बीज के लिए रखे थोड़े-से धान में से ही चुपचाप दो मुट्ठी निकाल कर लिये आ रही है। वह नहीं चाहती कि उसका पति इस विषय में कुछ जाने। उसका पति काम की तलाश में घोलवाड गया था और पूछताछ करने पर हमें पता चला कि वह परिवार कद-मूल खाकर जिंदा रह रहा है और यह अवस्था मई माह की है, जबकि कोसबाड से तीन मील दूर घोलवाड और बोर्डी में फल-बागानों में कभी कुछ काम मिल सकता है। यह परिवार अकेले भोजन पर ही १७५ रुपये मासिक खर्च करने के लिए कब आय कर सकेगा? क्या यह इस जीवन में कभी न्यूनतम जीवन-स्तर प्राप्त कर सकेगा? आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे लाखों परिवार हैं और उन पिछड़े वर्गों के लोगों को

तो छोड़ ही दीजिए जिनकी अवस्था इतनी ही दयनीय होगी। तीसरी योजना में हम एक खरब रुपये खर्च करने जा रहे हैं। परन्तु क्या उससे आदिवासियों की, जोकि हमारे समाज का केवल एक ही भाग है, बहुत ही दयनीय अवस्था में सुधार होने जा रहा है ?

आय में बढ़ता अन्तर

डा. धनजयराव गाडगिल के अनुसार पिछली दोनों योजनाओं के कार्यान्वय से अमीर और अमीर हुए हैं तथा गरीब और गरीब। हमारे प्रधान मंत्री के अनुसार धनी और धनी होते जा रहे हैं तथा निर्धन जहाँ के तहाँ हैं। जो भी हों, यदि पच वर्षीय योजनाओं के कार्यान्वय का अन्तिम परिणाम यही है तो हमारे आयोजन में कोई मूलभूत गलती है या फिर इसके कार्यान्वय में। हमारी तृतीय पच वर्षीय योजना की ७५० पृष्ठवाली पुस्तक में प्रथम वाक्य है: “भारतीय विकास का मुख्य उद्देश्य निश्चय ही भारतीय जनता को सुन्दर जीवन बिताने के लिए अवसर प्रदान करना है।” फिर, अध्याय ४ के पैरा १ का प्रथम वाक्य है “जिस समस्या पर तुरन्त ध्यान देना है वह है गरीबी तथा उससे पैदा होनेवाली बीमारियों का प्रतिरोध करना।” फिर पैरा ५ में कहा गया है कि गांधीजी के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति सिर्फ एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य लोगों को गरीबी और अयोग्यता से उबारना भी था। इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, यह इसी तथ्य से स्पष्ट है कि आय वितरण के विभिन्न पहलू योजना आयोग के लिए चिन्ता का विषय बन गये हैं। आय वितरण की पद्धति का अध्ययन करने हेतु प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की जो समिति नियुक्त की गयी है, वह यह सिद्ध करती है कि योजना आयोग समाज के विभिन्न अंगों में आय की बढ़ती असमानता के प्रति सचेत हो गया है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि राष्ट्रीय आयोजन सभी परिवारों के लिए

बुनियादी उपभोक्ता सामग्री की न्यूनतम उपलब्धि तथा सामाजिक सुविधाओं का प्राक्धान करे।

स्वचालन

प्रश्न है कि यह स्तर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। श्री वैकुण्ठ ल. मेहता ने इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं,—“राष्ट्रीय न्यूनतम में भी सर्वोपरि बात है—तुरत ही रोजगारी के अवसर बढ़ाना। बेशक लक्ष्य है उचित पारिश्रमिक पर पूर्ण रोजगारी की उपलब्धि।” परन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जा रहा है ? क्या इसके लिए कोई नियमित आयोजन है ? लगता है कि सारा आयोजन श्रम बचानेवाले यात्रीकृत भारी उद्योगों का तीव्र गति से विकास करने के लिए है। उद्योगपतियों का उद्देश्य यंत्रों का उपयोग कर तथा जन-शक्ति की कम से कम सेवा लेकर अपने उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाना है। हाल ही में मैंने एक समाचार पढ़ा कि पश्चिम जर्मनी के एक छोटे-से गाँव अलिगा की एक बड़ी दुग्धशाला (डैरी) इस प्रकार चलायी जा रही है कि अस्तबल साफ करने, मवेशी बाधने, उन्हें खिलाने, नहलाने, उनका दूध दुहने, बर्तनों में दूध भरने तथा बाद में उन्हें साफ करने, उनका मलमूत्र साफ करने तथा अन्य सभी सम्बन्धित कार्य यंत्रों से ही किये जाते हैं।

उक्त दुग्धशाला के मालिक श्री फ्रेडरिक बेरुहार्ड को एक ही प्रकार का शारीरिक श्रम करना पड़ता है और वह है अवलोकनार्थियों को चारों ओर घुमाना तथा स्वचालित यंत्रों द्वारा की जानेवाली विभिन्न प्रक्रियाएँ समझाना। इसी प्रकार रूस के एक वायुयान निर्माण कारखाने में सारा काम यंत्रों के जरिये ही किया जाता है। कारखाने को चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत है। वह एक विशेषज्ञ है और कारखाने से कुछ दूर पर बने अपने कार्यालय से ही सारी प्रक्रियाओं की देखरेख करता है। कारखाने के इन यंत्रों ने २,५०० व्यक्तियों को बेकार बनाया

हैं। बिजली के ऐमे-ऐमे औजार बनाये गये हैं जोकि मनुष्य की तरह काम करते हैं और मनुष्य की जगह खुद सभी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इसे तकनालॉजिकल प्रगति कहते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों ही विभाग इसके पीछे पागल हैं और यह तर्क देते हैं कि इसके बिना भारत आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में जिन्दा नहीं रह सकता।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत को अन्य उन्नत राष्ट्रों जितना उच्च और प्रगतिशील वैज्ञानिक स्तर प्राप्त करना ही चाहिए। लेकिन भारत की आबादी ४३ करोड़ है और यह प्रति वर्ष २ प्रति शत बढ़ रही है। इस विशाल और बढ़ रही आबादी के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे की जायगी और बिना तकनालॉजिकल तथा वैज्ञानिक प्रगति की राह में बाधक बने उनकी गरीबी और अशोणित किम प्रकार दूर की जा सकती है, यही असली समस्या है जिसने हमारे विचारकों और आयोजकों को उलझा रखा है।

श्री वैकुण्ठ ल० मेहता के अनुसार बड़े पैमाने पर रोजगारी देनेवाले कार्यक्रम में वह तकनीक अपनायी जानी चाहिए जोकि कुटीरोद्योगों के विकास के उपयुक्त हो, खासकर, आम मांग की उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन से सबबित हो। उन्होंने जापान का उदाहरण दिया है जिसने जानबूझ कर चन्द उद्योगों में तकनालॉजी का स्तर नीचा रखा है ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिले, उसका विस्फुरण हो। भारत में भीषण बेकारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए तो यह और भी जरूरी है। परन्तु उपभोक्ताओं

अथवा समाज पर बराबर यह बोझ न बना रहे, इसके लिए एक ऐसा कार्यक्रम तो होना ही चाहिए जिसमें तकनालॉजी के स्तर में धीरे-धीरे सुधार होना जाय। तथापि, मैं यह महसूस करता हूँ कि सिर्फ उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, जंगली क्षेत्रों के लिए वे उपयुक्त नहीं होंगे, जहाँ कि तीन करोड़ वन्य जाति के लोग रहते हैं। उनके मामले में तो छोटे पैमाने पर चलाये जानेवाले वन्य उद्योगों पर जोर दिया जाना चाहिए, जोकि सहकारी आधार पर चलाये जायें।

सभी जंगली क्षेत्रों में वन्य उद्योगों को आरम्भ करने के लिए जिनका आयोजन करना होगा उनमें से कुछ है आरम्भ किये जानेवाले वन्य उद्योगों की तकनीकों का वन्य जाति के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए जंगली क्षेत्रों में ही व्यवस्था करना उनमें से ही कुछ लोगों को इन उद्योगों का सगठक बनाने का प्रशिक्षण देना, आवश्यक वित्त और बिक्री-व्यवस्था का प्रावधान आदि। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे ये भाई कई पुस्त से इस गरीबी और अशोणित में रह रहे हैं। इसमें सुधार लाने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आजादी मिले पन्द्रह साल से भी अधिक गुजर चुके हैं और योजित विकास पर बहुत भारी रकम खर्च की जा चुकी है, लेकिन आदिवासियों के हालात में सुधार नहीं हुआ है। इसके विररीत, हालत और बिगड़ी ही है तथा बदतर हो गयी है। हमारे आयोजन का लक्ष्य इससे सबबित होना ही चाहिए।

बम्बई : २५ जुलाई १९६१

पिछले दशक में स्पष्टतः उत्पादन में प्रभावोत्पादक वृद्धि होने के बावजूद राज्य में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता आज भी राष्ट्रीय औसत से कम है।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात : नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

वालोद महाल विकास योजना : एक विवेचन

विमल शाह

इस लेख में गुजरात के सूरत जिले में स्थित वालोद महाल के समग्र विकास के लिए बनायी गयी योजना के अन्तर्गत किये गये प्रयासों का मूल्यांकन किया गया है।

गुजरात के सूरत जिला स्थित वालोद महाल क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी विकास सस्थाओं ने महाल के समग्र विकासार्थ एक साथ मिलकर एक पंच वर्षीय योजना बनायी है। यह योजना राज्य की तृतीय पंच वर्षीय योजना के साथ-साथ ही कार्यान्वित की जानेवाली थी अर्थात् १९६१ से १९६६ तक। योजना कार्यान्वय के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसने तीसरे में प्रवेश किया है। पिछले दो वर्षों के कार्यों की समीक्षा करना लाभप्रद होगा, क्योंकि इसमें, अब तक जो सफलता मिली है उसकी तथा योजना की शेष अवधि में जो प्राप्त करना बाकी रह गया है उसकी जानकारी मिलेगी।

महाल के ८० प्रति शत लोगो का मुख्य आधार कृषि है, अतः विकास योजना में स्वभावतः इसका प्रमुख स्थान है। कृषि एकमुश्त योजना के फलस्वरूप, जिसे कि समूचे जिले में लागू किया गया है, महाल योजना में कई कार्यक्रमो को शामिल किया जा सका और उनमें से कुछ ने तो लक्ष्य से भी अधिक सफलता प्राप्त की। उदाहरणस्वरूप, नयी क्यारी जोत तैयार करने तथा पुरानी क्यारी जोत की अवस्था सुधारने के कार्यक्रम में प्रथम दो वर्षों के लिए क्रमशः १०९ एकड़ और १,१०० एकड़ भूमि निश्चित की गयी थी, परन्तु असल में क्रमशः १९१ एकड़ और ४,००० एकड़ भूमि में काम किया गया। इसी प्रकार उर्वरको और मुअरे सरजामो के लागू करने तथा फलो के नये वृक्ष लगाने के कार्यक्रमो में भी लक्ष्य से अधिक काम हुआ।

इसके विपरीत बाघ बघाई और सिचाई के मामले में लक्ष्य से बहुत कम काम हुआ। चूँकि एकमुश्त अधिकारीगण इन कार्यों के लिए यात्रिक उपकरण प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति नहीं की जा सकी। कृषि के इन दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमो की कमी पर आयोजको को अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अन्ततः उनके ही सफल कार्यान्वय पर कृषि उत्पादन में वृद्धि निर्भर करेगा।

विकासकालीन कठिनाइयाँ

एकमुश्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के लिए ऋण मिलना आसान हो गया है। उदाहरणस्वरूप महाल में १७ बहुधवी और सेवा सहकारिताओं ने कृषि कार्यों के लिए १९६०-६१ में १,६०,००० रुपये अग्रिम दिया जबकि १९६२-६३ में १९ समितियो ने ३,३४,००० रुपये लघु कालीन ऋण दिये। इस प्रकार दो वर्ष के अन्दर इसमें १०० प्रति शत से अधिक वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ५० प्रति शत ऋण जिस के रूप में दिया गया, जिस कारण खाद की खपत काफी बढी। परन्तु इस समस्या का एक पहलू और है जोकि कार्यान्वय के वक्त सामने आया। पचास प्रति शत ऋण अनिवार्य रूप से जिस में प्राप्त करने के नियम से १९६२-६३ में किसानो को बडी तकलीफ हुई क्योंकि इस वर्ष सिर्फ ३० इंच ही बारिश हुई जबकि पिछले वर्ष ७९ इंच बारिश हुई थी। इतनी कम बारिश होने पर किसान अच्छी बारिश के समय

जितनी मात्रा में ही उर्वरक इस्तेमाल करने की जोखिम नहीं उठा सके। फिर भी, नियमानुसार उन्हें पूरा कोटा लेना पड़ा, जिसे कि उन्हें अपने घरों में जमा कर देना पड़ा, जिससे कि पूँजी एक गयी।

फिर, १९५७ के काशन अधिनियम के अन्तर्गत काश्तकार जमीन के मालिक बन गये, जिसके लिए उन्हें न्यायालय द्वारा निश्चित कीमत चार में बारह एक-सम किस्तों में देनी थी। इसने तथा एकमुश्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े ऋण ने चुकती के मामले को मुश्किल बना दिया था। किसान अपनी फसल में से पहले भूमि की कीमत की किस्त चुकाने को मोचता है क्योंकि देर होने से जमीन के छिन जाने का डर है। उसके बाद भूमि राजस्व का नम्बर आता है। और उसके बाद सहकारी समिति के ऋण को चुकाने का, जिसने एकमुश्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उसे ऊँची दर पर ऋण दिया है। हा, यह कह सकते हैं कि ये प्रारम्भिक कठिनाइयाँ हैं। परन्तु वे कठिनाइयाँ तो हैं ही और यदि उचित उपाय नहीं किया गया तो विकास में बाधा पहुँचने का अदेशा है।

जैसा कि बताया जा चुका है, इस अवधि में सामान्य बारिश भी नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप फसल पद्धति में बहुत परिवर्तन हुए। सन् १९६२-६३ में कम बारिश के कारण धान, दाल, गेहूँ और कपास के खेत में कमी हुई और ज्वार तथा मूँगफली के खेत में वृद्धि। वर्षा के प्रभाव के अतिरिक्त मूँगफली के खेत में निरंतर वृद्धि और कपास के खेत में कमी होती गयी। कपास की खेती में कमी का कारण है पिछले कुछ वर्षों से कपास की फसल पर कीड़ों का आक्रमण। बारडोली के चीनी कारखाने द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के फलस्वरूप गन्ने के खेत में भी निरंतर वृद्धि होती गयी। पशु पालन विकास कार्यक्रम ने कोई प्रगति नहीं की है।

सहकारी संगठन

इस अवधि में सहकारी संगठन भी काफी मजबूत

हुआ है और कई मदों में इसने लक्ष्य की प्राप्ति की है। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ी है और उनके सदस्यों की भी, हिस्सा पूँजी और लाभ में भी वृद्धि हुई है। नयी किस्म की सहकारी समितियों का भी गठन हुआ है। उदाहरणस्वरूप इस अवधि में तीन कृषि सहकारी समितियाँ, एक मजदूर ठीका समिति, एक ताड़ गुड़ उत्पादक समिति, एक दुग्ध उत्पादक समिति और एक उपभोक्ता भंडार का संगठन किया गया है। कपास ओटाई और गाठ बघाई समिति ने इस अवधि में मूँगफली का प्रशोधन और बिक्री कार्य भी हाथ में ले लिया है। फिर भी, जहाँ तक महाल में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री और प्रशोधन का प्रश्न है, बहुत कुछ करना बाकी है। इसे ऋणदात्री संस्थाओं से सम्बन्ध बनाये रखते हुए करना है। तभी सुरक्षित रूप में ऋण दिया जा सकेगा। अभी तो ऐसा चन्द किसानों के मामले में ही हुआ है। अधिकांश को तो इसका लाभ प्राप्त है ही नहीं।

औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुटीर दियासलाई और हाथ कागज उद्योगों को हाल ही में आरम्भ किया गया है। पिछले दो वर्षों में सघन क्षेत्र संगठन ने अपने कारखाने में नये ढंग के बालवाडी और स्कूली उपकरणों का निर्माण आरम्भ किया है। वालोद में एक नया तेल-कोल्हू बैठाया गया है और गैर-सरकारी क्षेत्र में धातु उद्योग का विस्तार हुआ है। महाल में औद्योगिक विकास का उपयुक्त वातावरण निर्मित किया गया है और भारी तथा लघु दोनों ही किस्म के नये उद्योगों को आरम्भ करने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है, जैसे धान के डठल से कार्ड-बोर्ड बनाना तथा स्थानीय रूप में उपलब्ध धातुओं से खपरैल बनाना। पिछले दो वर्षों में महाल में जो नयी औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू हुई हैं, उनमें १०० से भी अधिक लोगों के लिए काम के नये अवसर निर्मित हुए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी लक्ष्य की प्राप्ति हुई है

अथवा उससे अधिक काम हुआ है। इस अवधि में पाच किडरगार्तेन स्कूल और एक हाई स्कूल खोला गया है जबकि प्राइमरी स्कूलों के लिए २४ स्कूली कमरे बनाये गये हैं। स्कूल में पढ़नेवाले लड़कों की भी संख्या बढ़ी है और पढ़ानेवाले शिक्षकों की भी, तब प्रति शिक्षक ४४ के बदले ३७ विद्यार्थी का अनुपात बैठता है। महाल हेड क्वार्टर से १२ मील दूर बारडोली में आर्ट्स एंड साइन्स कालेज खुल जाने तथा आवागमन की सुविधाएँ उपलब्ध होने से यहाँ के विद्यार्थियों के लिए कालेज की शिक्षा प्राप्त करना भी संभव हो गया है। बालोद में विज्ञान मंदिर ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और अब यह महाल के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

बालोद में पानी टकी के निर्माण का भी कार्य पूरा हो चुका है तथा उन्हें तीन और जगहों में आरंभ करने की तैयारी की जा रही है। सभी गाँवों में

पीने के पानी की सुविधाएँ उपलब्ध करना अभी बाकी ही है क्योंकि पाच वर्ष में ५० कुएँ खोदने के लक्ष्य में से अभी सिर्फ चार ही खोदे गये हैं। चार गैस सयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा और शीघ्र ही बैठाये जानेवाले हैं। सन् १९६३-६४ में बालोद में बिजली भी आ जायेगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पिछले दो वर्षों में महाल में चतुर्मुखी विकास हुआ है। यह सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के फलस्वरूप ही हो सका है। ऐसा ही वातावरण बने रहने और तालुका पंचायत के संगठन के जरिये विकास कार्यों को सक्रियता प्रदान करने से ऐसी आशा की जाती है कि पंचवर्षीय विकास योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो जायेगी।

बालोद (गुजरात) . १५ अक्टूबर १९६३

सन् १९५१ के जनगणना-आंकड़ों की गणना के अनुसार ५८ प्रति शत आबादी की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि और उससे सम्बन्धित कार्य है। सन् १९५५-५६ में इस विभाग के लोगों का राज्य की आय में योगदान २ अरब २५ करोड़ रुपये रहा अर्थात् कुल का ४४ प्रति शत। प्रति एकड़ उत्पादन का मूल्य राष्ट्रीय औसत का करीब दो-तिहाई है। इतनी कम उत्पादकता का मुख्य कारण है निम्न कोटि की फसल पद्धति और अधिकांश प्रमुख फसलों का न्यून उत्पादन, जिनके लिए राज्य के अधिकांश भाग में प्रतिकूल जलवायु अवस्थाओं को दोषी ठहराया जाता है।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात: नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।



मैंने खादी ग्रामोद्योग के दिम्बर् १९६३ के अंक में 'रेशम कीट-पालन' समस्याएँ और सम्भाव्यताएँ' नामक लेख पढ़ा। यह बहुत ही रुचिकर और सुन्दर ढंग से लिखा गया है। तथापि, मैं एक दो तथ्यपूर्ण गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

पृष्ठ २३६ के पैरा २ में यह लिखा है कि शहतूत की पत्तियों की प्रति एकड़ उर्ज करीब १० हजार पौण्ड बायिक है। परन्तु यह औसत उत्पादन नहीं हो सकता। यह तो व्यवहार्य पश्चिम बंगाल के मालदह जिले का औसत उत्पादन है। अन्य स्थानों के मामलों में यह कम है।

उसी पृष्ठ पर पैरा ३ में यह बताया गया है कि फिलहाल देश के उत्पादन में करीब ६५ प्रति शत हिस्सा 'निस्ट्री' कोशों का है। यह सही नहीं है। 'निस्ट्री' बहु-जननशील देशी कोश है और यह सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता है। मैसूर, कश्मीर और रेशम उत्पादन करनेवाले अन्य राज्यों में उनकी अलग ही जानिया—एफ १ क्रास और विदेशी दोनों ही किस्म की—होती है। अतः यह कड़ना गलत होगा कि 'निस्ट्री' देश का उत्पादन है।

कलकत्ता

११ दिसम्बर १९६३

—सत्य रंजन सेन

निर्देशक (रेशम)

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन

पाली में एकमुश्त कार्यक्रम

माखन लाल भट्ट .

चुनिदा जिले में कृषि का सघन विकास करना 'एकमुश्त कार्यक्रम' का उद्देश्य है। प्रस्तुत लेख में प्राप्त सफलताओं पर विचार किया गया है, और इसके सफल कार्यान्वय के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं।

राजस्थान का पाली जिला, कृषि उत्पादन पर फोर्ड फाउण्डेशन दल ने जिला कृषि कार्यक्रम—जो 'एक-मुश्त कार्यक्रम' के नाम से प्रसिद्ध है—की जो सिफारिश की उसके अनुसार प्रारम्भिक चरण के रूप में सात राज्यों में, जिन जिलों का चयन हुआ उनमें से एक है। यह कार्यक्रम विभिन्न विदेशों में, खास कर संयुक्त राज्य अमेरिका में, सफलतापूर्वक चलाया जा चुका है। कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कृषि विकास में खाद्यान्नों की उपज में पर्याप्त वृद्धि करना शामिल है, जोकि हमारे वर्तमान अस्तित्व को बनाये रखने और भावी आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के साधन व विधियाँ हैं (अ) उत्पादन-वृद्धि के लिए 'अनुकूलतम' अवस्थाओंवाले चुनिन्दा क्षेत्रों में उपलब्ध सीमित साधन-स्रोतों पर ध्यान केन्द्रित करना, (आ) वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के सर्वाधिक प्रभावकारी तरीकों व उपायों को प्रत्यक्ष करके दिखाना, और (इ) सिचाई तथा सुनिश्चित जल-पूर्ति-युक्त अन्य अनुकूल क्षेत्रों में इस प्रकार के सघन कृषि कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए विधि यानी तौर-तरीके तथा अन्य आवश्यक बातें निर्मित करना।^१

मुख्य विशेषताएँ

पाली जिले का क्षेत्रफल ३० लाख १८ हजार एकड़ है और आबादी ८ लाख ७ हजार। एकमुश्त कार्यक्रम के कार्यान्वय से पूर्व विशुद्ध रूप से १३ लाख १ हजार

एकड़ भूमि पर खेती होती थी। इस जमीन को ८१ हजार परिवार जोतते थे। खेत का औसत आकार १६ १७ एकड़ था। कुल ९१ हजार यानी प्रति खेतिहर परिवार पीछे १९ एकड़ भूमि ऐसी थी, जिस पर खेती हो सकती थी, पर की नहीं जाती थी। जितने क्षेत्र में खेती होती थी उसका २४ ५४ प्रति शत सिंचित क्षेत्र था। प्रति एकड़ औसत उपज यद्यपि राजस्थान के वर्षा पर निर्भर रहनेवाले अन्य क्षेत्रों से अधिक थी पर अखिल भारतीय स्तर से कम। प्रति कर्मी विशुद्ध योगदान और विशुद्ध कृष्य क्षेत्र की प्रति एकड़ कृषिक-आय अनुमानत समग्र राजस्थान से कम थी, जोकि क्रमशः २७० और ६२ रुपये थी।^२ इसका कारण किसी हद तक निम्न कोटि की फसलों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र का होना था, जोकि क्षेत्र में कम वर्षा होने की वजह से था।

इस पृष्ठभूमि में १९६३-६४ के अतः तक समग्र क्षेत्र को कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के उद्देश के साथ १९६१ की खरीफ की फसल से प्रारम्भिक तौर पर जिले के दस खण्डों में से सात में एकमुश्त कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम का कुल परिव्यय १ करोड़ १० लाख रुपये था। कार्यक्रम के अन्तर्गत १० लाख ६८ हजार एकड़ जमीन लाने और २३ लाख टन उर्वरक वितरित करने की कल्पना की गयी थी। लघु-कालीन ऋण ९ करोड़ १२ लाख ४९ हजार रुपये और मध्य-कालीन ऋण ३ करोड़ ६० लाख रुपये तक देने की

१ इन्टेशिव एग्रीकल्चरल प्रोग्रैम (पैकेज प्रोग्रैम) खाद्य और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (मेमो)।

२ टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान नेशनल कौन्सिल ऑफ अग्रइंड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

व्यवस्था की गयी। अपेक्षा की गयी थी कि पूरी तौर मे कार्यान्वित होने पर जिले के ६५ प्रति शत परिवार तथा कुल कृष्य भूमि का २५ प्रति शत क्षेत्र इसके अन्तर्गत आ जायेगा और १९५९ के २ लाख २१ हजार टन कृषि उत्पादन के स्थान पर १९६५-६६ मे वह बढ़ कर ३ लाख ४० हजार टन हो जायेगा।^३

प्रथम दो वर्षीय काल मे—जोकि प्राप्त परिणामो के मूल्यांकन के लिए बहुत ही लघु अवधि है—कार्यक्रम के अन्तर्गत १८ हजार परिवार तथा एक लाख एकड़ भूमि (लक्ष्याक का २२२ प्रति शत और करीब १२५ प्रति शत) आयी बनायी जाती है। लगभग १२ हजार नये खेतिहर परिवार १९६३ की खरीफ के दौरान और आठ हजार १९६३-६४ की रबी फसल के दरमियान कार्यक्रम के अन्तर्गत आनेवाले हैं, जिसका मतलब है जिले के करीब ३८ प्रति शत खेतिहर परिवारो का कार्यक्रम के अन्तर्गत आना। यहाँ यह स्मरणीय है कि लक्ष्याक ३५ प्रति शत कृषि परिवारो का था। जो उर्वरक तथा उन्नत बीज वितरित किये गये उनका परिमाण क्रमश २० टन और २२ हजार ७०० टन था।

तालिका १

प्रति एकड़ तुलनात्मक उपज
(पीण्ड मे)

	ज्वार	बाजरा	मक्का	गेहूँ	जव
फार्म योजना	४११	३२८	९६६	१,१६७	१,१६१
गैर-फार्म योजना	३००	२६१	८२६	९५१	१,१०३
फार्म योजना मे					
गैर-फार्म योजना					
से अधिक औसत					
प्राप्ति	३७	२५	६७	१६	९५
	२२	७१	६५	८०	

स्रोत 'क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेण्ट ऑफ पैकेज प्रोग्रैम—प्रिलिमनरी र्पनलेसिस'।

३ पैकेज प्रोग्रैम—हैन्ड्स एण्ड फिंगर्स विस्तार निर्देशालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

तथापि, ऐसा लगता है कि वृद्धि-दर 'फार्म योजनाओं' तक ही सीमित है, शेष भूमि में कोई परिवर्तन नहीं आया जैसा कि ऊपर तालिका १ से प्रकट है।

यह एक स्पष्ट मकेत है कि कृष्य क्षेत्र के एक मामूली हिस्से में ही उत्पादकता बढ़ी है और इसलिए जिले के समग्र उत्पादन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा है। वस्तुतः चन्द किस्मो के उत्पादन मे गिरावट आयी है।

जिले का चुनाव

एकमुश्त कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के लिए फोर्ड फाउण्डेशन के विशेषज्ञ दल ने यह कसौटी रखी कि (अ) क्षेत्र मे कम से कम प्राकृतिक रुकावटो होनी चाहिए, (आ) उसमें मुनि-श्चित जल-पूर्ति हो, और (इ) सहकारी समितियो, पचायतो आदि जैसी संस्थाएँ उसमें सुविकसित हो। पाली जिला ये शर्तें पूरी नहीं करता था और पिछले तीन वर्ष से उक्त कार्यक्रम इसमें चलने के बावजूद अवस्थाओं में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, प्रथम, जिले मे बारह मास तथा स्थायी स्वरूप की सिचाई-व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र का करीब ७६ प्रति शत भाग वर्षा पर निर्भर है, जिसका होना अनिश्चित है, उस पर निर्भरना एक प्रकार मे जोखिम से परिपूर्ण है और वह अपर्याप्त है। अधिकांश कुए, जिनकी संख्या २४,७३९ है और जो क्षेत्र के करीब २४ प्रति शत भाग की मिचाई के लिए जिम्मेदार है, ऐसे हैं जिनके पानी मे अम्लत्व है और फलस्वरूप वह जमीन को कृषि के लिए अयोग्य बना देता है।

द्वितीय, वर्षा का न होना जोकि कोई असा-मान्य बात नहीं है। इसके फलस्वरूप सूखा और अकाल पडता है तथा लोगो को अपने मवेशी लेकर एक स्थान मे दूसरे स्थान पर भी जाना पडता है, जिससे उनकी जीव्यता यानी सजीवता को ठेस पहुँचती है और भूमि विकास के प्रति

उनका अभिक्रम व प्रयास डीला पड़ जाता है, फिर सीमा करीब २०० रुपये रखी गयी है, जबकि वास्त-चाहे आविष्कारों, योजनाओं आदि पर उनका कितना विक आवश्यकताएँ एक अच्छे श्रीगणेश के लिए ८२५ ही भरोसा क्यों न हो। तृतीय, गृहकारिताएँ जैसी और १,६५० रुपये के बीच की है। इसके आलावा पहले से ही किसानों की आवश्यकताएँ जानने की कोई सस्याएँ अभी अपने शीशव-काल में हैं और उनके सदस्य प्रभावशाली विधि नहीं है। यह कि किसान अपनी अनपढ़ तथा फिरका-पगस्ती के शिकार हैं। सामा-

तालिका २

विभिन्न फसलों का उत्पादन

(हजार टन में)

वर्ष	ज्वार	बाजरा	गेहूँ	जव	चना	मक्का
१९५९-६०	० ७६	० २६	० ६७	० ३२	० ०७	० १५
१९६०-६१	० ११	० १९	० ५०	० २७	० ०२	० २६
१९६१-६२	० २२	० ३४	० ७१	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य

स्रोत : 'स्टेटिस्टिकल अब्स्ट्रेक्ट ऑफ राजस्थान', १९६१।

न्यत ये सस्याएँ अब भी ऊँची जातिवालों, भूतपूर्व जमींदारों या साहूकारों के नियंत्रण में हैं, जोकि इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रति हृमदरं नहीं है। एकमुस्त कार्यक्रम शुरू करने से पहले जिले में केवल १७८ कृषि सहकारी समितियाँ थीं और उनके सदस्यों की संख्या १६,००० ही थी अर्थात् ३२ प्रति शत आबादी ही उनके अन्तर्गत आती थी। इन समितियों के साधन-स्रोत सीमित होने की वजह से १९६० तक वे प्रति कृषक औसतन रूप से २६ रुपये से अधिक अर्जि नही दे सकी।

ब्याज की उपयुक्त दर पर और उपयुक्त समय पर सहकारी समितियों के माध्यम से उधार देना इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मूल मंत्र अथवा रामबाण औषधि है, लेकिन विभिन्न कारणों से ये सस्याएँ अब तक अपने सदस्यों को उत्पादन तथा उनकी पारीवारिक आवश्यकताओं के लिए पूरा ऋण प्रदान करने में असमर्थ रही हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए वे साहूकारों के चंगुल में फँसते हैं। यह भी सच है कि वर्तमान हिस्सा-पूजी के अनुसार २५ रुपये औसत हिस्सा पूजी के आकार पर एक व्यक्ति के लिए अधिकतम उधार लेने की

ठीक-ठीक उपभोग आवश्यकताएँ भी पूरी करने में असमर्थ हैं, इसलिए यह एक ऐसा कारक है कि उत्पादन के लिए वह जो उधार पाता है उसे उपभोग के लिए काम में लाने को बाध्य हो जाता है। स्वभावतः और अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए समितियाँ अधिका-अधिक रूप से दिवालिया तथा अयोग्य बन जाती हैं एवम् तदनुसार ऋण के लिए प्रार्थना करनेवाले परिवारों की संख्या कम हुई है।

अब तक हुए अनुभव से पता चलता है कि दुधारू पशु और बैल खरीदने जैसे कामों के लिए मध्य-कालीन ऋण की मांग पूरी नहीं की जा सकी। यदि ऐसे ऋण दिये भी गये तो वैसे मामलों में अदायगी एक वर्ष के भीतर करने की शर्त रखी गयी, जिसे पूरा करना शायद ही सम्भव था। ऋण स्वीकार करने में जहाँ पर सम्पत्ति की गारण्टी की बात आती है, अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं। इन कठिनाइयों में आवश्यक मात्रा तथा उपयुक्त समय पर ऋण न मिलने की बात भी आती है, जो भूमिहीन श्रमिकों के लिए खास तौर पर सामने आती है। बताया जाता है कि कार्यक्रम में किसान अपना विश्वास खोने जा रहे हैं,

क्योंकि समय पर रमद तथा उधार मुहैया नहीं की जा सकी है। द्वितीय, 'ऋण शोधानिधीय' स्वीकार करने का दबाव होने के कारण सम्बद्ध अधिकारिग्रा के लिए ऋण के लिए प्रार्थना पत्रों में लिखित बातों की झूठ-साच का पता लगाना सम्भव नहीं बन पड़ा है।

उपयुक्त प्रणाली यह होगी कि गारण्टी आदि में

उत्पादन के लिए दिया गया ऋण फसल में प्राप्त उत्पादन की बिक्री में वसूल किया जा सके।^४ इस सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है, वह बहुत ही सीमित है और सहकारिताओं के जरिये उधार के क्षेत्र में हुए विस्तार से तुलना करने पर वह नगण्य बन जाती है। अब तक जितना ऋण दिया गया है उसका मुश्किल

तालिका ३

वर्ष	कुल अग्रिम दी गयी रकम (लाख में)	समितियाँ की सन्ख्या	योग्य घोषित सहकारिताओं की मदस्य-संख्या ममिनियाँ मदस्य	ऋण के लिए प्रार्थी परिवारों की संख्या
१९६१ खरीफ	१००० }	२४९	६१३ ४०,४४३	(अप्राप्य)
१९६१ रबी	५५० }			
१९६२ खरीफ	६०९ }	१३९	३५६ ४०,१५१	४,५३९
१९६२ रबी	०५३ }			

स्रोत 'रिड्यू ऑफ प्रॉमिस मेड इन १९६२-६३'।

सम्बन्धित नियमों की औपचारिकताओं सरल बनाया जाय। यदि सभी सहकारी ममिनियाँ बहु-उद्देशीय प्रकार की हों, तो ऋण की वापसी यानी वसूली आसान हो सकती है। जहाँ तक सम्भव हो ऋण जिन्स के रूप में देना अच्छा होगा। ऐसा करने से न केवल ऋण का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि किसान को अपनी बचत में से पूरक 'आदा' (इनपुट) की पूर्ति करने की प्रेरणा भी मिलेगी। इस प्रकार इसका परिणाम निकलेगा अर्थ-व्यवस्था में अधिक निवेश।

दूसरा पक्ष इस बात से सम्बन्धित है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी रकम उत्पादन कार्य में इस्तेमाल की जाय तथा ऋण की वापसी समय पर हो। इसमें निरीक्षण अथवा देख-रेख के लिए ठोस प्रबन्ध की बात आती है और इन सब के अलावा यह भी कि उधार व बिक्री-व्यवस्था के बीच निकट सम्पर्क हो, ताकि

से ३३ प्रति शत हिस्सा वापिस वसूल किया जा सका है। इसका कारण यह है कि ऋण वसूल करने के लिए सहकारी समितियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर बिक्री-व्यवस्था संगठन का प्रादुर्भूत हाल ही में हुआ है। खरीद करने के लिए वहाँ के दो बिक्री संगठनों के पास रुपया-पैसा नहीं है और उत्पादन के श्रेणी-विभाजन में उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं।^५ इन ममिनियों के सामने आवश्यक व्यवस्थापकीय कर्मचारियों की अपर्याप्तता और वित्त की कमी की समस्याएँ भी हैं। इस प्रकार इन समितियों के जरिये उत्पादन की बिक्री करना वाछनीय होगा या नहीं, यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

^४ एग्रीकल्चरल सिच्यूएशन इन इण्डिया भारत सरकार; मार्च १९६२, वार्षिकांक १९६१ और १९६२।

^५ टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान . नेशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली, १९६३।

सहकारी मस्याओं से लिए गये ऋण अविक हो जाने और उनकी वापसी न किये जाने के अन्य कारण इस प्रकार हैं (अ) व्यक्ति कितना ऋण वापस कर सकता है, इस दृष्टि में उसकी क्षमता से अधिक ऋण देना, और (आ) जिन व्यक्तियों का कुछ प्रभाव है वे समय पर ऋण की वापसी नहीं करते, जिसका प्रभाव अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। इन में से कुछ तो हैं ही ऐसे कि वे आदतन रूप से ही वापसी नहीं करते और जिन्होंने उधार मुविधा का लाभ उठाया है तथा इस प्रकार समूची समिति के काम को प्रभावित किया है, उसे दूषित किया है।^६

एकमुश्त कार्यक्रम के अन्तर्गत यद्यपि कृषि योजनाएँ एक मौसम के लिए ही बनायीं और कार्यान्वित की जाती हैं, तथापि बाड़े की खाद, उर्वरक व जमीन तैयार करना—जिसके लिए ऋण दिया जाता है—आदि जैसे कुछ ऐसे मद हैं जिनका खरीफ और रबी दोनों ही फसलों पर प्रभाव पड़ता है। फार्म आयोजक को उसे खरीफ के मौसम में जितना ऋण दिया जाता है, वह सब का सब दिसम्बर के महीने में एक किश्त में वापस करना पड़ता है। इसके अलावा खरीफ की फसल खेतों में खड़ी रहते हुए ही उसे रबी की फसल के लिए ऋण प्राप्त करना पड़ता है। चूँकि खरीफ की फसल रबी की फसल की बोआई करने के वक्त तक भी खड़ी रहती है, इसलिए इस सम्बन्ध में नियमों में कुछ ढिलाई करना तथा अधिकतम उबार की सीमा को कुछ और ऊपर उठाना आवश्यक है।

एक वृत्त में योजनाएँ बनाने का लक्ष्याक ऐसे ही निर्धारित कर लिया जाता है। उसमें योजनाओं की सम्भाव्यताओं का ध्यान नहीं रखा जाता और इस प्रकार ऐसी योजनाएँ अधिकांशतः वास्तविक नहीं होती। लक्ष्याक सामने रखे रहने, अकुशलता के लक्षण और दण्ड से बचने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता प्रायः बड़ी जल्दी-जल्दी में तथा सम्बद्ध किसान की बिना स्वीकृति लिये

ही योजनाएँ बना लेते हैं। लक्ष्याक इतने ऊँचे होते हैं कि क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता उन्हें प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। इससे उनके काम के गुण में गिरावट आती है। कार्यक्रम केन्द्रित न हो कर काफी विस्फुरित यानी विस्तृत होने के कारण भी उक्त बात पैदा होती है।

कुछ मामलों में ऐसा पाया गया कि अनुवर्त्ती सेवा का अभाव है। इसके कारण बादवाले मौसम में लोगों की ओर से प्रत्युत्तर में कमी आती है। इसके कारण ये हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्याधार ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता हैं तथा उनका कार्यक्षेत्र सामान्यतः बहुत विस्तृत होता है और रोजमर्रा की कागजी कार्रवाई के अलावा उन्हें और भी अनेक काम करने पड़ते हैं।

कार्यक्रम विदेशी अनुभव पर आधारित है। सभी मान्यताएँ और लक्ष्याक विदेशों के गाँवों की गणनाओं आदि पर आधारित हैं, जोकि सामान्यतः हो सकता है कि भारतीय अवस्थाओं में प्रयोग करने लायक न हो। इस भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं, उदाहरणार्थ, मिट्टी की रचना, जलवायु, धरातल आदि या फिर आबादी का घनत्व, पूजा की उपलब्धि, सामाजिक रीति-रिवाज व धार्मिक मान्यताएँ आदि। इसके अलावा “यूरोपीय तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित हमारे यहाँ के कृषि विशेषज्ञ सदैव ही इस काम के लिए उपयोगी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके विचार प्रायः अधिक कल्पना-प्रधान होते हैं”.....“इसमें जोखिम यह है कि आधुनिकतम तकनीकों के लिए अत्यधिक उत्साही बाहरी विशेषज्ञ अथवा स्थानीय अधिकारी अल्प-विकसित क्षेत्रों में निहित पहलू का बिना खयाल किये आगे बढ़ सकते हैं।”^७ और फिर, अनपढ़ तथा रीति-रिवाजों से बन्धे अथवा

७ यूनाइटेड नेशंस प्रोसीडिंग्स ऑफ साइन्टीफिक कॉन्फ्रेंस ऑन कजरवेशन में ‘इंटर अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल सर्विसेस’ के प्रोफेसर एल्बर्ट र्होड (Albert Rhoad) की प्रमाणोक्ति।

चिपके हुए कृषक तीव्र व क्रांतिकारी परिवर्तन अपनाने के जो आदि नहीं हैं, भौतिक प्रगति को साधारणतया कम महत्व देते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो आधुनिकता को, सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन के अधिक वाछनीय लक्ष्यों की तुलना में, हीन समझते हैं। हमारी प्रगति में यह पहलू एक मुख्य बाधा रहा है और आज भी बना हुआ है। अतएव कार्यक्रम की उपयुक्तता व क्षमता और परिवर्तनों की शक्यता के सम्बन्ध में कृषकों की दिलजमी करने के लिए स्वाभाविक रूप से ही महान प्रयास करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम की प्रगति में अवरोध के लिए जिम्मेदार हैं पचायतों तथा सहकारिताओं के बीच वैमनस्य का होना — पचायत राज्य के अन्तर्गत ग्राम विकास के लिए उत्तरदायी ये दोनों ही बुनियादी संस्थाएँ हैं और गांव की नेतागिरी अपने हाथ में रखने के लिए दोनों ही एक-दूसरी से स्पर्धा कर रही हैं। इन संस्थाओं पर ऐसे शक्तिशाली गुटों का नियन्त्रण है, जिनकी ग्राम विकास में शायद ही कोई दिलचस्पी हो। एकमुश्त कार्यक्रम को—जोकि एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए—वर्तमान अवस्था में इन संस्थाओं में से कोई भी अपना कार्यक्रम नहीं समझती। इसलिए इस दिशा में कदम उठाने आवश्यक है कि ये संस्थाएँ मिल कर समरसता के साथ काम करें।

भावी कार्यक्रम

उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कार्यक्रम को निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से सफलता हासिल करनी है तो उसका पुनर्गठन करना पड़ेगा और अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर पुनः प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी पड़ेंगी। इसके लिए निम्न कदम उठाने आवश्यक हैं

१ कृषि को वर्तमान जिन्दा भर रहने की अवस्था से बदल कर व्यावसायिक प्रकार देना होगा, ताकि कृषक अधिकतम विशुद्ध लाभ प्राप्त कर सके।

२ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले से सृजित सुविधाओं के अनुकूलतम उपयोग को प्राथमिकता देने और ऐसी योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है, जिनसे कम लागत पर पर्याप्त अधिक प्राप्ति हो।

३ कृषकों की कुल आय अधिकतम बनाने की दृष्टि से इस क्षेत्र के अब तक उपेक्षित पशु-धन के विकास को कृषि विकास के साथ जोड़ा जाय।

४ वर्तमान विकास विधि या स्वरूप जो रूढ़िगत है अर्थात् जिसमें लचीलापन नहीं है और जिसमें ऊपर से विकास करने के मार्ग निर्धारित करने की प्रवृत्ति है, उसे बदला जाय। कार्यक्रम में अधिक लचीलापन होना चाहिए और विकास किस प्रकार किया जाय, इसका निर्धारण किसी निश्चित आधार पर न करके स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार किया जाय।

५ एक ही साथ ऐसी अनेक योजनाएँ शुरू करने की प्रवृत्ति से बचा जाय जोकि कर्मचारियों की कमी आदि जैसे कारणों से चलायी नहीं जा सकती और जिनमें प्रयास व्यर्थ जाते हैं।

६ कृषि विकास का कार्यक्रम कुछ सुवारात्मक उपाय कार्यान्वित करके अथवा प्राथमिकताएँ निर्धारित करके थोड़े-थोड़े रूप में नहीं चलाया जा सकता। कार्यक्रम से तभी अनुकूलतम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जबकि उसे एक सुसंयोजित यानी ठोस रूप में कार्यान्वित किया जाय। इस उद्देश्य के लिए अधिक विस्तृत क्षेत्र अपनाने की अपेक्षा—जोकि वर्तमान पद्धति है—सघन प्रयास करने के लिए छोटा कार्यक्षेत्र अपनाना चाहिए।

७ इन सब उपायों अथवा कदमों की सफलता उन्हें उपयुक्त रूप से कार्यान्वित करने पर निर्भर करती है। यह तभी सम्भव है, जबकि सघन रूप से प्रचार-प्रसार करके तथा अन्य कदम उठा कर कृषक को

योजना की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विश्वास दिला पर निर्भर रहने जैसी समस्याओं पर अपना ध्यान दिया जाय। केन्द्रित करना चाहिए।

८ एकमुश्त कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारियों को सर्व प्रथम (अ) जल की पूर्ति, (आ) चने और जव में होनेवाले 'रूखडी' नामक रोग का अवरोध, (इ) प्रतिरोधी बीजों की पूर्ति, (ई) खाद तथा मल-मूत्र के प्रयोग-खास कर मिचित क्षेत्रों में-को लोकप्रिय बनाने, और (उ) आधिकारिक तौर पर रखे गये प्रात्यक्षिक प्लाटों की अपेक्षा फार्म योजना

यद्यपि एकमुश्त कार्यक्रम से क्षेत्र में प्राप्त भूत-कालीन सफलताएँ साधारण हैं, तथापि यदि स्थानीय अवस्थाओं और वातावरण के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए सुसंयोजित व ठोस एवम् सघन प्रयास किये जाय तो इस क्षेत्र में विकास के लिए महान क्षमता निहित है।

वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) • ४ नवम्बर १९६१

राज्य के दक्षिणी हिस्से अरब सागर के उत्तरी छोर पर बसे हैं जहाँ कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। अतः बारिश राज्य के दक्षिणी सिरे पर बसे बलसार में १९१ सेंटीमीटर होती है और फिर वह धीरे-धीरे घटती जाती है, जैसे सूरत में १०४ सेंटीमीटर और अहमदाबाद में ७४ सेंटीमीटर होती है, जोकि करीब १५० मील के दायरे में है। इसके साथ ही बारिश पर भरोसा भी बहुत कम हो जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में भिन्नता ३० प्रति शत से अधिक है। प्रायः बारिश स्थानीय रूप से होती है और कहीं-कहीं ही होती है।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात: नेशनल
कॉउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

रेशम उद्योग व रेशम अनुसंधान

कमल बनर्जी

केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के तत्वावधान में बरहमपुर और कालिम्पोंग में रेशम कीट-पालन में अनुसंधान करने सम्बन्धी जो गतिविधियाँ हैं उनका और कोया पालन व रेशम उत्पादन के उन्नत और-तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए जो कदम उठाये गये हैं उनका, प्रस्तुत लेख में संक्षिप्त मूल्यांकन किया गया है।

गुप्त तीन शताब्दियाँ में पश्चिम बंगाल में मुंशिदाबाद का प्रधान उद्योग रेशम रहा है। इसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जिले की ओर आकर्षित किया, जहाँ डच, फ्रांसीसी और आर्मेनियन उक्त उद्योग के क्षेत्र में उनके प्रतिस्पर्धी थे। मॉन ट्रेवरनियर (Mon Traverrier) ने लिखा था, “मन्त्रहरी शताब्दी के मध्य तक बंगाल में कुल रेशम उत्पादन करीब २५ लाख पौण्ड था। इसमें से दस लाख पौण्ड स्थानीय रूप से काम में लाया जाता था, साढ़े-सात लाख पौण्ड का डच निर्यात करते थे और साढ़े-सात लाख पौण्ड भारत तथा मध्य एशिया में वितरित होता था।” उद्योग की सम्पन्नता इस शताब्दी के प्रारम्भ में धीरे-धीरे करके गिरने लगी और दो महायुद्धों व देश-विभाजन के कारण पैदा हुई गड़बड़ी से उद्योग बिल्कुल तबाह हो गया। इसी बीच जापानी रेशम उद्योग की कड़ी स्पर्धा का मुकाबला भारतीय रेशम उद्योग के सामने एक गम्भीर समस्या का रूप ले चुका था। फिर भी, रेशम कीट-पालन ने इन सभी प्रकार की स्पर्धाओं के होते हुए भी मुंशिदाबाद के सबसे बड़े कुटीर उद्योग के रूप में अपनी स्थिति बनाये रखी।

सरकारी प्रयास

रेशम कीट-पालन में सुधार करने के लिए बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ने ही १९४६ में बरहमपुर नामक स्थान पर केन्द्रीय रेशम कीट-पालन

अन्वेषण केन्द्र की स्थापना की तथा कालिम्पोंग में उसका एक उप-केन्द्र खोला। राज्य सरकार ने दोनों ही स्थानों पर अन्वेषण केन्द्र को मुफ्त में जमीन और इमारत दी तथा भारत सरकार ने अन्वेषण केन्द्र व उप-केन्द्र की वित्तीय व्यवस्था करने का वचन दिया। शुरू-शुरू में पश्चिम बंगाल के रेशम कीट-पालन को प्रभावित करनेवाली समस्याओं का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के रेशम कीट-पालन उप-निर्देशक को निर्देशक के रूप में नियुक्त कर अन्वेषण केन्द्र का प्रारम्भ लघु स्तर पर किया गया था। उस समय लड़ाई में पैराशूट रेशम की बहुत अधिक जरूरत थी और अंग्रेजों के आश्रित भारत—उस वक्त मैसूर एक रजवाड़ा यानी गियासत थी—में रेशम उत्पादन के लिए बरहमपुर ही एक मात्र उपयुक्त केन्द्र के रूप में स्वीकार किया गया।

उस समय जबकि रेशम उद्योग बड़ी तीव्रता के साथ गिरना जा रहा था रेशम व्यापारियों की एक समिति ने रेशम के कीड़ में आनेवाली बीमारी से लड़ने के उपाय ढूँढ़ निकालने और रेशम कोया-पालन में ‘पैशचर्य’ पद्धति का समावेश करने की कोशिश की। सन् १९०८ में तत्कालीन बंगाल सरकार ने कृषि निर्देशालय के अन्तर्गत यह प्रयोग किया और बंगाल रेशम समिति गठित की गयी, जिसके अध्यक्ष थे कृषि-निर्देशक। बंगाल के रेशम कीट-पालन व्यवस्थापक के अन्तर्गत बरहमपुर में एक रेशम कीट-पालन फार्म खोला गया और मुंशिदाबाद तथा मालदा जिलों में सरकारी फार्मों में रेशम कीट-पालन

अनुसंधान शुरू किया गया। आज की तरह वास्तविक रूप से कच्चे रेशम का उत्पादन मुख्यतः मालदा जिले में होता था। बुनकरो के लिए मुंशिदाबाद प्रसिद्ध था। बरहमपुर स्थित केन्द्रीय पौधशाला आज भी रेशम कोया-पालन और शहतूत की बागबानी के तरीके में सुधार करने के लिए काम करती है।

वर्णसंकरीय-प्रजाति

सरकारी पौधशालाओं में जिन प्रमुख भारतीय रेशम कीटों का पालन किया जा रहा था उनमें 'निस्ट्री' और 'छोटा पोलू' मुख्य थे। वर्ण संकरीय अभिजनन के लिए अनेक अन्य प्रजातियाँ भी लायी गयीं। उस समय बरहमपुर में सी सी घोष नामक एक सज्जन रेशम कीट-पालन के व्यवस्थापक थे। उन्होंने कुछ जैव विशेषज्ञों की सहायता से वर्ण संकरीय अभिजनन के लिए अन्वेषण प्रारम्भ किया। खास करके डाक्टर डी सी सरकार तथा डाक्टर एम एल दासगुप्त जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति थे, जो बाद में चल कर महान जीवशास्त्रियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतीय रेशम कीटों की निस्ट्री प्रजाति में गर्मी सहने की शक्ति होती है और वह बहु-जननशीलता (मल्टी-बोल्टाइन) विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस प्रजाति में अनेक उत्पत्त्यावर्तन (साइकल्स ऑफ प्रोडक्शन) होते हैं। किन्तु निस्ट्री प्रजाति से उत्पादित रेशम अनेक विदेशी प्रजातियों से प्राप्त, विशेष कर जापानी प्रजाति से प्राप्त, रेशम के मुकाबले निम्न कोटि का होता है। किन्तु निस्ट्री जहाँ बहुजननशील है वहाँ जापानी प्रजातियाँ एको-जननशील अथवा द्वि-जननशील हैं। इसलिए भारतीय तथा विदेशी प्रजातियों के मिश्रित यानी वर्णसंकरीय अभिजनन के जरिये रेशमी कीड़ों की एक नयी नस्ल के सृजन की दिशा में प्रयास किये गये।

केन्द्रीय रेशम कीट-पालन अनुसंधान केन्द्र यद्यपि १९४३ में स्थापित हुआ तथापि, अनेक कारणों से वह १९६० तक कोई उल्लेखनीय काम नहीं कर सका। बाद में भारत सरकार ने बरहमपुर में केन्द्रीय रेशम

कीट-पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना पर स्वीकृति दी, जोकि भारत में सबसे बड़ा अन्वेषण केन्द्र है और केन्द्र के भवन तथा प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु १८ लाख रुपये मंजूर किये। बरहमपुर के पूर्वी छोर पर पचाननटोला में नये भवन का निर्माण पूर्णविस्था में है।

वास्तविक अन्वेषण

सन् १९६१ से उक्त अनुसंधान केन्द्र वर्णसंकरीय अभिजनन के सम्बन्ध में वस्तुतः कुछ वास्तविक अन्वेषण कार्य कर रहा है और इस प्रकार रेशम-कीड़ों की नयी प्रजातियों का निर्माण कर रहा है, जोकि रोग-मुक्त होंगे तथा जिनमें परिमाणात्मक कोया मूल्य होगा। निस्ट्री और एक जापानी प्रजाति के सहभोग से बरहमपुर में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, जबकि मालदा में जापानी और चीनी प्रजातियों को लेकर प्रयोग चल रहे हैं। बरहमपुर केन्द्र में चन्द ऐसी अजरबेजान प्रजातियों को ले कर प्रारम्भिक अन्वेषण हो रहा है, जो स्थानीय प्रजातियों के सहवास से उत्पन्न हुई हैं। चयनकारी अभिजनन और बेहतर रूप से पालन करके स्थानीय प्रजातियों में सुधार लाने के लिए स्थानीय रेशम कीट-पालक अधिक ध्यान देते हैं, तथापि व्यावसायिक दृष्टि से वे कितनी योग्य हैं, यह अभी देखना है। परिमाणात्मक और गुणात्मक दृष्टि से मूल्यांकन, कोया पालने के लिए अनवरत अन्वेषण तथा परीक्षण करते रहना ही एक मात्र मार्ग है, ताकि बगाल का रेशम उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा कर सके।

मुंशिदाबाद में

मुंशिदाबाद जिले में फिलहाल १,२११ एकड़ भूमि पर शहतूत की खेती होती है और वहाँ का रेशम उद्योग प्रति वर्ष कोई छ लाख पौण्ड रेशम कोये पैदा करता है। यह जिला प्रति वर्ष तीन लाख वर्ग गज रेशमी वस्त्र और ६० हजार पौण्ड कच्चा रेशम तैयार करता है। रेशम के कीड़े शहतूत की कोमल पत्तियाँ खाते हैं, और

मुनियोजित शहतूती बागवानी रेशम कीट-पालन की एक पूर्व शर्त है। किसी समय इस जिले में—बाम कर जिले के सदर उप-प्रमण्डल में—शहतूत के विस्तृत बागान थे। बेलडागा थाने के गाँव कभी शहतूती बागवानी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन समय पाकर जब रेशम कीट-पालन के बुरे दिन आये तो इन गाँवों की उस भूमि में जहाँ पहले शहतूत के बागान थे सब्जी और अन्य खाद्यान्नों की फसलें बोयी जाने लगी। अब शहतूत की बागवानी के अन्तर्गम और अधिक क्षेत्र लाने तथा शहतूती पौधों से अच्छी प्राप्ति के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि स्वस्थ कोये पाले जा सकें। चूँकि प्रति वर्ष शहतूत के ताजा पौधे लगाने पर जोर दिया जाता है, इसलिए उक्त काम प्रति वर्ष कृषकों को पौधशालाओं से शहतूत की नयी कलमें प्रदान करते हुए किया जाता है।

कोया-पालन का स्तर

मुशिदाबाद और मालदा के गाँवों में कोया-पालन एक ऐसा उद्योग है जो छोट-छोटे खेतों में होता है। प्रत्येक कोया-पालक, जिसे स्थानीय बोल-चाल की भाषा में 'बसनी' कहते हैं, साधारण खेती के अलावा कुछ बीघा जमीन पर शहतूत के पौधे भी लगाता है। मुशिदाबाद जिले में फिलहाल कोया-पालन करनेवाले परिवारों की संख्या ३,००० से कम नहीं है और गत वर्ष रेशम कीट-पालन सम्बन्धी पौध-शालाओं ने उन्हें ३०,००० शहतूती कलमों की पूर्ति की। पश्चिम बंगाल सरकार की बेलडागा थाने के कुमारपुर नामक स्थान पर एक कलम पौधशाला है। शुरू में इसकी वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीय रेशम मण्डल ने की थी। इसकी स्थापना १९५५-५६ में हुई। बाद में इस कलम पौधशाला को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया और पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों के रेशम-कीट-पालकों को

उसने हजारों कलमों की पूर्ति की।

विभिन्न प्रकार की खाद, उर्वरक और तौर-तरीके सावधानी पूर्वक उपयोग में लाते हुए अच्छे गुण-स्तर की शहतूती पत्तियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम कीट-पालन अनुसंधान केन्द्र में विस्तृत प्रयोग भी किये जा रहे हैं। मत्तोपप्रद फल प्राप्त हुए हैं और इस बात के भी प्रमाण हैं कि परिमाणान्तरक तथा गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों में शहतूत की खेती में सुधार हुआ है। शहतूत की खेती के लिए प्रायः सिचाई की समस्या है और राज्य सरकार ने शहतूत की खेती करनेवालों को सिचाई पम्पों की पूर्ति करने की व्यवस्था की है। शहतूत की खेती जिस जमीन पर होती है उसकी सिचाई करने और उसमें खाद डालने के लिए कृषकों को ऋण दिया जाता है। राज्य सरकार ने १९५७-५८ में ६५० शहतूती कृषकों को ऋण दिया।

उन्नत तौर-तरीकों का प्रचार

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने रेशम उत्पादन के अभिनव तौर-तरीकों का प्रचार किया है, करती है, और राज्य के रेशम कीट-पालन विभाग के प्रात्यक्षिक दल गाँवों में रेशम कीट-पालकों को कोया-पालन के उन्नत तौर-तरीके सीखाने के लिए नियमित रूप से जाते रहते हैं। कोया-पालकों को स्वस्थ रेशम कीट प्रदान किये जाते हैं, ताकि वे बेहतर और एकसम गुणवाले कोयों का उत्पादन कर सकें। सन् १९६० के अन्त तक ७४,५६० 'चन्द्रिकाओं' से दूसरी 'अवस्था' तक पालन करके ऐसे स्थानीय कोया-पालकों को कोयों की पूर्ति की गयी, जिन्होंने राज्य के रेशम कीट-पालन विभाग के मार्गदर्शन में उन्नत तौर-तरीकों का व्यवहार करते हुए कोया-पालन अपनाया।

मुशिदाबाद : ६ अगस्त १९६३

सामाजिक अनुसंधान की भूमिका

सोमसुन्दर यशवन्त

भारत में समाजशास्त्री को इस बात का अध्ययन करना पड़ेगा कि परम्परा यानी रीति-रिवाज तथा जाति जैसे उनके अन्यान्य रूपों का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये आन्तरिक तथा बाह्य शक्तियों का प्रतिरोध करते हैं और उन्हें खपा लेते हैं, एवम् वह आधार प्रस्तुत करते हैं जिस गुटबन्दी अवस्थित होती है।

समाज रचना का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में ही नहीं बल्कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी समाज अलग-अलग होते हैं। एक अल्प-विकसित देश में जिसकी उत्पादकता कम हो, सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक अनुसंधान के साथ करने की आवश्यकता है। हमारा भारतीय समाज वशानुगत परम्परा पर आधारित एक गुटबन्दी का शिकार समाज है। इस सम्बन्ध में जाति वह आधार है, जिस पर गुटबन्दी अवस्थित है। वस्तुनिष्ठ अध्ययनों से पता चलता है कि “इन पक्षों अथवा गुटों का विरोधात्मक कार्यों में बहुत बड़ा हाथ है जैसे ग्राम्य एकता और किसी भी प्रकार के सहकार में अनवरत बाधा, अशान्ति को बढ़ावा और व्यक्ति तथा सम्पत्ति के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही, मुकद्दमेबाजी, पारस्परिक फूट और दलबन्दी को प्रोत्साहन।”^१ और फिर, “असन्तोष, पारस्परिक कटुता, गुटबन्दी असाक्षरता, अज्ञान जाति-भेद, दलगत दंगे-फसाद, सामाजिक तनाव भीषण बेरोजगारी”^२ भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताएँ हैं। परिणाम-स्वरूप ग्रामीण जनता के दुख-दर्दों को समाप्त करने पर बहुत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। समाजशास्त्री अथवा मानव-

शास्त्री को उन बुनियादी तत्वों का अध्ययन करना चाहिए जिन पर यह गुटबन्दी आधारित है, जबकि नीति निर्माताओं को ये बुराइयाँ कम करने और अन्ततोगत्वा समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

सामाजिक अनुसंधान के लिए क्षेत्र

सामाजिक अनुसंधान के सगठन में बेतुके तौर-तरीकों से बचना चाहिए और कार्य-विधि का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न निदर्शकों के साथ वैज्ञानिक उपागम होना चाहिए। उदाहरण के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आनेवाले और उसके बाहर के गाँव में विभेद करना चाहिए। इन विकास योजनाओं के शुरू होने के बाद गाँवों में जो परिवर्तन आये हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए भी इनमें विभेद किया जाना चाहिए। सुधार लागू करना आसान है, लेकिन उनके व्यवहार का मूल्यांकन करना मुश्किल है।

समाज-व्यवस्था की खामियों को मोटे रूप में सामने रखने की दृष्टि से समाजशास्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। “सामाजिक समस्याओं के समाधान में सिद्धान्तवादी समाजशास्त्री को अपनी सामाजिक निर्माता की भूमिका निभाने के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देना है। सामाजिक सम्बन्धों के बारे में अपने विशिष्ट ज्ञान के कारण समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन लाने और सामाजिक प्रगति को गति प्रदान करने में सहायता दे सकता है, वह

१ बलजीत सिंह • नेक्स्ट स्टेप इन विलेज इण्डिया;

पश्चिमी पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९९१, पृष्ठ ६।

२. उक्त उद्धृत, पृष्ठ ४।

तन्मन्त्रन्धी भविष्यवाणी कर सकता है, उन पर नियन्त्रण रख सकता है और निर्देशन दे सकता है।”^३

अलग विज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। सामाजिकशास्त्री सामान्यतः यह स्वीकार करते हैं कि एक अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं आबादी का एक बहुत बड़ा अनुपात—सामान्यतः ७०-८० प्रति शत—ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जो अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। समाज में कोई विशेष बचत नहीं होती। अधिकांश खर्च भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर होता है। इस प्रकार इसमें इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि व्यापार आदि के न्यून परिमाण क्यों हैं, रहन-सहन की अवस्था खराब है। अन्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं कृषि तकनीकों का निम्न स्तर, अत्यधिक कर्ज, उच्च जन्मानुपात तथा मृत्योनुपात, जीवन रहने की कम आशा, न्यून पोषण व मार्बजनिक स्वास्थ्य का निम्न स्तर, बाल-श्रम, अत्यधिक अशिक्षा—खाम कर महिलाओं में—महिलाओं का निम्न दर्जा, आदि।

परम्परा

भारतीय समाजशास्त्रीय विचार-धारा पर परम्परा की शक्ति के कारण विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सामाजिक परम्पराओं का उन्हें प्रभावित करने-वाली आन्तरिक तथा बाह्य शक्तियों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि परम्पराएँ इन शक्तियों का प्रतिरोध करती हैं और इन्हें खपा लेती हैं। रिवाजों, लोक-रीतियों और लोकाचार का विस्तार में अध्ययन करना पड़ेगा। भारतीय परम्परा की रुढ़ि-

वादिता जानिवाद के प्रचलन का अध्ययन कर समझी जा सकती है। यह परम्परा का ही परिणाम है कि उसने अन्य संस्कृतियों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। उसकी गत्यात्मकता ही कमजोर पड़ी है, किन्तु उसे पूर्णतः नश्वरताबूद नहीं किया जा सका है।

उपसंहार

परिमाणात्मक तथा गुणात्मक यानी दोनों ही दृष्टियों से सामाजिक अध्ययन के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, उन पर आयोजित उपागमों के जरिये काबू पाया जा सकता है। भाषा, जाति, रीति-रिवाज और पारिवारिक जीवन जैसे पहलुओं को सामाजिक अध्ययन का ब्राडकास्ट करके समझा जा सकता है। ये अध्ययन यदि आत्मनिष्ठ दृष्टि से किये गये तो अलग-अलग होंगे लेकिन मानवीय सीमा के कारण आत्मनिष्ठवाद तो एक ही पहलू है, जो अध्ययन में आता है। “दो मानवशास्त्री एक ही फिरके अथवा गँव के बारे में लिखें तो भी कुछ ऐसा लिखेंगे कि उन दोनों का वर्णन अनेक मामलों में एक-दूसरे में भिन्न होगा।”^४ और, समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री की भूमिका प्रायः एक समान ही है। भारत में सामाजिक अनुसंधानकर्ता को परम्परा तथा जाति आदि जैसे उसी के अन्य रूपों का परिवर्तनों पर जो बहु-विध प्रभाव पड़ा है, उसकी पृष्ठ-भूमि में अपना अध्ययन करना पड़ेगा और उन प्रभावों का अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके तथा अपने अध्ययन के बीच सम्बन्ध स्थापित करना होगा।

मद्रास २९ जून १९६३

३ डी एन मजूमदार : आर एन सक्सेना द्वारा सम्पादित सोशल, सोशल रिसर्च एण्ड सोशल प्रॉब्लेम्स इन इण्डिया में, पृष्ठ : १२-१३।

४. एम. एन श्रीनिवास : इण्डिया'ज विलेज, पृष्ठ : ४।

ग्राम्य जीवन में स्थिरता और परिवर्तन

ग्राम सर्वेक्षण के मालूमात

सुभाष चन्द्र सरकार

सन् १९६१ की जनगणना के अग स्वरूप तैयार किये गये ग्राम सर्वेक्षण 'मोनोग्राफों' से ग्राम समाज की मौजूदा स्थिति पर इस विशेष सन्दर्भ में अच्छा प्रकाश पड़ता है कि वहाँ संचार की समस्या कैसी है और स्वयम् ग्राम समाज में परिवर्तन के लिए कितनी इच्छा व क्षमता है।

सन् १९६१ की जनगणना के प्रतिवेदन की एक अपनी विशिष्टता है उसमें ग्राम सर्वेक्षण 'मोनोग्राफों' का होना, जिनका उद्देश्य महा-पञ्जीयक और जनगणना आयुक्त श्री अशोक मित्र के शब्दों में "यह जानना है कि गाँव कितना यानी किस हद तक गतिहीन है और वैसा होते हुए भी वह कितना बदल रहा है तथा परिवर्तन की हवा किस वेग से व किधर से बह रही है।" सामान्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कम से कम पैंतीस गाँवों का सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण मोनोग्राफ के लिए चुने गये गाँवों के मामले में आँकड़ों से जो अर्थ निकलता है अर्थात् जो चित्र सामने आता है, उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत पर्यवेक्षण किया जाता है। लिखित वर्णन के साथ पूरक के रूप में वास्तविक जन-जीवन के तथा जिस भौतिक वातावरण में वे रहते हैं उसके और खेतों में जिन उपकरणों का वे इस्तेमाल करते हैं उनके चित्र होते हैं।

प्रस्तुत सन्दर्भ में जिन 'मोनोग्राफों'* का जिक्र है उनके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के तीन गाँव आते हैं, जनगणना कार्यवाहियों के सुपरिण्टेण्डेंट श्री जे सी सेन गुप्त के अनुसार पचास गाँवों का सर्वेक्षण किये जाने की योजना है। चूकि पश्चिम बंगाल देश का एक सर्वाधिक

औद्योगिक और शहरीकृत राज्य है, इसलिए इन सर्वेक्षणों से—जोकि शहरी क्षेत्रों के पास के दो गाँवों (कोदालिया और कामनारा) तथा राज्य के भीतरी ग्रामीण क्षेत्र के एक गाँव (घाटमपुर) से सम्बद्ध हैं—देश में औद्योगीकरण व शहरीकरण की प्रगति और सीमा के विषय में दिल-चस्प चित्र सामने आता है।

कोदालिया चन्दननगर से करीब दो मील और हुगली-चिनसुरा के भी नजदीक ही है, जोकि जिले तथा प्रमण्डल (डिवीजन) का भी सदरमुकाम है। गाँव के लोग अन्य स्थानों में रेलगाड़ियों, सार्वजनिक बसों, मोटर कारों (चाहे गाँववालों में से कोई भी उनका मालिक न हो तब भी) तथा साइकल रिक्शों के माध्यम से जा-आ सकते हैं। अनेक ग्रामीण वास्तव में आस-पास के कस्बों में और यहाँ तक कि कलकत्ता में भी—जो वहाँ से २० मील पड़ता है—काम की तलाश करते हैं, मिलने पर काम करते हैं।

इसी प्रकार कामनारा बर्दवान-कटवा सड़क पर बर्दवान से करीब तीन मील है। आस-पास के शहरी इलाकों में आसानी से जाने-आने की दृष्टि से कामनारा की स्थिति भी कोदालिया के समान ही है।

इसके दूसरी ओर घाटमपुर गाँव उद्योग-प्रधान

*सेन्सस ऑफ इण्डिया १९६१, वॉल्यूम १६, वेस्ट बंगाल, भाग ६, ग्राम मोनोग्राफ। रचितता पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए जनगणना कार्यवाहियों के सुपरिण्टेण्डेंट

जे सी सेन गुप्त, नयी दिल्ली, १९६१, पृष्ठ. ११ (प्रस्तावना)+३५, ९ (प्रस्तावना)+३१, और ९ (प्रस्तावना)+३५, मूल्य क्रमश २.२० रुपये, २.८० रुपये, और २.९० रुपये।

हुगली जिले में ठीक ग्रामीण क्षेत्र के बीच बसा है। जिले के सदर मुकाम चिनमुगा से वह १६ मील दूर है। सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन गाँव की उत्तरी सीमा में आधे मील की दूरी पर है, लेकिन निकटतम बस का रास्ता तीन मील पड़ना है और इसी प्रकार डाकघर (गाँव के लोगों को एक पत्र तक डालने के लिए तीन मील दूर माखनपुर डाकखाने तक जाना पड़ता है)।

यह उल्लेखनीय है कि तीनों गाँवों में रेल की लाइन प्रत्येक को दो भागों में विभाजित करती हुई जाती है।

गाँवों की आबादी का आकार भिन्न है—ग्रामीण क्षेत्र में बसे गाँव की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के समीपवर्ती गाँवों की जनसंख्या ज्यादा है। कोदालिया में १८२ परिवार हैं और जनसंख्या ९२२ कामनारा में परिवार १५० हैं और आबादी ९३०। इसके विपरीत घाटमपुर में १५० घर हैं और जनसंख्या ७२७ है। आबादी बहु-जाति-प्रधान है तथा एक में तो बहु-धर्मावलम्बी है।

विस्थापन

तीनों ही मामलों में विस्थापकों यानी अन्य स्थानों से आकर बसे लोगों की संख्या काफी अधिक है। कोदालिया में ५० घर तो इसी पीढ़ी में आकर बसे हैं, जबकि आठ परिवार एक पीढ़ी पहले आकर बसे थे। कामनारा में वर्तमान पीढ़ी में आये परिवारों की संख्या अड़सठ है, जबकि उनतीस पिछली पीढ़ी में आये थे। घाटमपुर में सोलह परिवार इस पीढ़ी में आये और पन्द्रह एक पीढ़ी पहले। किसी भी गाँव से कोई भी परिवार दूसरे स्थान पर जाकर बसा हो ऐसा नहीं बताया गया।

लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं, यह उनकी जाति के अनुसार भिन्न है, जिससे मोटे तौर पर उनकी आर्थिक अवस्था का संकेत मिलता है। कोदालिया में सबसे ज्यादा घर कर्मकारों के हैं। उनमें किसी के भी पक्का मकान नहीं है। गाँव में सादगोपो के और ब्राह्मणों के इक्कीस-इक्कीस घर हैं जिनमें से क्रमशः १८ तथा १७ परिवार पक्के मकानों में रहते हैं। गाँव में पक्के मकानों की कुल संख्या ५३ है। कामनारा में मात्र चार घर ही पक्के हैं। इनमें से दो मकान दो उग्र-क्षत्रियों के हैं, जिनमें से

एक गाँव में नहीं रहता। शेष दो पक्के मकानों में से एक में स्कूल है और दूसरे में छात्रावास। देहाती क्षेत्र के घाटमपुर में १५० परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिनमें से १४४ घरों की दिवाले कच्ची हैं, तीन परिवार बास की टाटियों में बनायी गयी दीवारोंवाले घरों में रहते हैं और तीन अन्य परिवार ईंटों में बने घरों में।

पेशेवार वितरण

गाँवों का पेशेवार वितरण निम्न तालिका से दृष्टव्य है

गाँवों का पेशेवार विभाजन

	कोदालिया	कामनारा	घाटमपुर
कुल परिवार संख्या	१८२	१५०	१५०
कृषि	४	६८	४९
खेतिहर मजदूरी	३८	२५	७७
उत्पादन कार्य	—	१२	७
पशु-धन	१०	—	३
निर्माण-कार्य	५	—	—
थोक व्यापार	१८	—	—
फुटकर व्यापार	२७	३	२
यातायात, भाण्डारीकरण			
व संचार	३५	१	१
अन्य सेवाएँ	३९	३१	४
गृह कार्य	६	—	—
जो कर्मी नहीं हैं	—	१०	७

कामनारा और घाटमपुर में अधिकांश आबादी अब भी खेती पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि कोदालिया में भी खेती से जीविकोपार्जन करनेवाले परिवारों की संख्या बावन है। हम देखेंगे कि घाटमपुर में आधी से ज्यादा आबादी अपने गुजर-बसर के लिए खेतिहर मजदूरों का काम करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के नजदीक के गाँवों में खेतिहर मजदूरों का कुल जनसंख्या के प्रति अनुपात कम है। इस पर इस सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि द्वितीय कृषि जाच में बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में भूमिहीन खेतिहर परिवारों का प्रातिशत्य १९५६-५७ में ६३ ४९ था। यद्यपि कोदालिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो काम नहीं करता हो, काम न रहनेवाले वर्ग में आनेवाले परिवारों की संख्या

घाटमपुर में सात और कामनारा में दस थी। सम्भवतः सब से उल्लेखनीय बात तो यह है कि कोदालिया एक शहरी क्षेत्र के बहुत ही नजदीक बसा है और आसानी से बिजली प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसमें कोई उद्योग नहीं है। वहाँ औद्योगीकरण एक दूर की चीज ही बनी हुई है। उत्पादन कार्य पर निर्भर करनेवाले कामनारा के १२ परिवारों में से आठ परिवारों के मुखिया पास के एक स्थान पर चावल मिल में काम करते हैं। (इससे भी यही प्रकट होता है कि ग्रामीण जीवन में धान हाथ कुटाई उद्योग के स्थान पर—जोकि रोजगारी का स्रोत होने के अलावा चावल खानेवालों के लिए पौष्टिक तत्वों का स्रोत भी है—अवाञ्छित प्रकार का औद्योगीकरण आ धमका है।) दो परिवारों के प्रधान बर्दवान के लोको शेड (वह स्थान जहाँ रेलगाड़ी के इंजन साफ-सफाई के लिए रखे जाते हैं) में काम करते हैं, एक घर का मालिक मिठाई बनाकर गाँव के बाहर बेचने का काम करता है, जबकि एक परिवार का मुखिया ऊन के कम्बल बुनता है।

पृष्ठ ३२२ और ३२३ पर १ गयी तालिकाएँ इस सम्बन्ध में विस्तृत आकड़ प्रस्तुत करती हैं।

ऋण तथा अल्प पोषण

पेशेवार विभाजन सम्बन्धी तालिकाओं से विभिन्न वर्गों के लोगों की जीवनावस्थाओं के चित्र की कल्पना करना कठिन नहीं है। कोदालिया के १८२ परिवारों में से ९९ यानी ५४ प्रति शत परिवार कर्जदार हैं। कामनारा में ७३ परिवारों पर ऋण का भार है। घाटमपुर में ११९ परिवार कर्जदार हैं। इस गाँव में केवल ३१ परिवारों पर ही ऋण नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अनेक परिवार अल्प-पोषित हैं।

प्रस्तुत तीन गाँवों में से किसी में भी बिजली नहीं है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि तीनों गाँव औद्योगिक वृत्त यानी क्षेत्र में अथवा उसके नजदीक हैं—दो गाँव तो शहरी क्षेत्रों के बहुत ही निकट हैं। इस कथन में यह तथ्य भी सामने रखने की आवश्यकता है कि कोदालिया में

पूर्वी रेलवे के 'इन्स्पेक्टर ऑफ वर्क्स' के घर में बिजली है। कोदालिया के १०३ घरों में हैरीकैन लालटेन जलाई जाती हैं और ७८ में चिमनियाँ। किसी भी घर में पेट्रोमेक्स अथवा गैस की लालटेन नहीं है। श्री सेन गुप्त लिखते (पृष्ठ ९) हैं कि "रहन-सहन के स्तर से आँकने पर ७८ परिवारों को गरीब किसानों की श्रेणी में माना जा सकता है।" कामनारा में ९१ परिवार लालटेन जलाते हैं और ५९ घरों में चिमनियाँ अथवा डिब्बों का उपयोग होता है। घाटमपुर में ७० परिवारों में लालटेन का और शेष ८० घरों में चिमनियाँ का इस्तेमाल होता है।

यातायात

यदि मिट्टी के तेल से जलनेवाले स्टोव को औद्योगिक युग का निदर्शक समझा जाय तो कोदालिया के १५४ प्रति शत परिवारों के लिए ही यह माना जा सकता है कि उन्होंने औद्योगिक युग में पदार्पण किया है। कामनारा में यद्यपि ५३ परिवार विशुद्ध रूप से अथवा लकड़ी के साथ-साथ ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पष्टतः वहाँ कोई भी स्टोव का उपयोग नहीं करता। इसी प्रकार घाटमपुर में केवल तीन परिवारों यानी दो प्रति शत घरों में ही स्टोव है।

साइकल को यदि औद्योगिक युग का प्रतिनिधि माना जाय तो हालत यह है कि कोदालिया के १८७ प्रति शत और कामनारा के १३३ प्रति शत घरों में साइकल है, किन्तु घाटमपुर के एक भी घर में साइकल नहीं है।

शिक्षा का विस्तार

तीनों ही गाँवों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हैं। यदि सभी परिवार अपने बच्चों को पढ़ने भेजने में समर्थ नहीं हैं तो इससे यह बात इतनी नहीं प्रकट होती कि वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, जितनी यह कि वे बच्चों की शिक्षा का खर्च बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं। स्कूल में लड़के अथवा लड़की की शिक्षा पर औसत खर्च कोदालिया में अमूमन तीर पर १५० और घाटमपुर में ४१ रुपये होता है।

कोढालिया गाँव के परिवारों का जाति और पेशे के अनुसार विभाजन

जाति	कृषि	कृषि श्रमिक	पशु धन	निर्माण कार्य	यानायात, भंडारी करण व संचार	थोक व्यापार	फुटकर व्यापार	अन्य सेवाएँ	गृह कार्य
ब्राह्मण	—	—	—	१	—	५	६	९	—
वैद्य	—	—	—	—	—	—	—	५	—
कायस्थ	—	—	—	१	१	—	—	४	—
सादगोप	१	—	—	—	—	—	४	१५	१
ग्वाला	—	—	९	—	४	७	१	—	—
दौरी	—	१०	—	—	३	—	—	—	३
बागडी	—	२	—	—	३	—	२	—	—
कर्मकार	२	२३	—	३	७	—	११	—	२
राजपूत	—	—	—	—	१	६	—	२	—
हरिजन	—	—	—	—	३	—	—	—	—
कुर्मी	१	१	—	—	१	—	—	—	—
दुसाध	—	१	—	—	२	—	—	—	—
रजवाड	—	—	—	—	२	—	—	—	—
मल्लाह	—	—	—	—	१	—	२	—	—
साव	—	—	१	—	२	—	—	—	—
साहा	—	—	—	—	—	—	—	१	—
महिश्य	—	—	—	—	—	—	—	१	—
धोबी	—	—	—	—	—	—	—	१	—
अम्बाटी (आघ्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से आये कृषक)	—	—	—	—	१	—	—	—	—
भुइया	—	—	—	—	१	—	—	—	—
पासी	—	—	—	—	१	—	—	—	—
रमानी-कहार	—	—	—	—	१	—	—	—	—
वैष्णव	—	—	—	—	—	—	—	१	—
भोर	—	—	—	—	१	—	—	—	—
तेली	—	—	—	—	—	—	१	—	—
राजवंशी	—	१	—	—	—	—	—	—	—
योग	४	३८	१०	५	३५	१८	२७	३९	६

टिप्पणी : औद्योगिक वर्गीकरण भारत सरकार के श्रम और रोजगार मन्त्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महा निर्देशक द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार किया गया है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्रमण्डल (डिवीजनल) वाणिज्य और व्यवसाय को दो भागों- थोक तथा फुटकर व्यापार-में विभक्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य सेवाएँ भी दो भागों-अन्य सेवाएँ तथा गृह कार्य-में विभक्त की गयी हैं।

कामनारा के परिवारों का जाति और घर के मालिक द्वारा अपनाये गये पेशे के अनुसार विभाजन

जाति या फिरका	कृषि	कृषि श्रमिक	उत्पादन कार्य	फुटकर व्यापार	यातायात, भाडारी- करण व संचार	अन्य सेवाएँ	कार्य गृह
ग्वाला या गोप	२९	—	—	१	—	—	५
सताल	१२	८	५	—	—	८	—
उग्र क्षत्रिय	९	१	३	१	१	३	२
बौरी	२	३	२	—	—	११	—
बागडी	—	९	१	—	—	३	२
नामशूद्र	११	२	—	—	—	—	—
मोची	४	२	—	—	—	—	—
गध वणिक	१	—	—	१	—	१	१
ब्राह्मण	—	—	—	—	—	२	—
वैरागी	—	—	—	—	—	२	—
अहीर	—	—	१	—	—	—	—
हरी	—	—	—	—	—	१	—
योग	६८	२५	१२	३	१	३१	१०

घाटमपुर के परिवारों का जाति/फिरका/समुदाय और घर के मालिक के पेशे के अनुसार विभाजन

जाति/फिरका/समुदाय	कुल परिवार	कृषि	कृषि श्रमिक	उत्पादन कार्य	फुटकर व्यापार	अन्य सेवाएँ	पशु धन	यातायात, भाडारी- करण व संचार	गैर कर्मों
मुसलमान	२६	१७	५	—	१	—	—	—	३
सादगोप	२४	१४	२	४	१	१	—	१	१
कोडा	१९	३	१६	—	—	—	—	—	—
कावडा	१५	२	११	—	—	—	—	—	२
देसवाली	१४	२	१२	—	—	—	—	—	—
कर्मकार	१३	—	१२	—	—	—	—	—	१
बौरी	१२	१	११	—	—	—	—	—	—
ग्वाला	११	७	—	—	—	१	३	—	—
ब्राह्मण	६	३	—	३	—	—	—	—	—
बागडी	५	—	५	—	—	—	—	—	—
भूमिज	३	—	३	—	—	—	—	—	—
परमाणिक	१	—	—	—	—	१	—	—	—
क्षत्री	१	—	—	—	—	१	—	—	—
योग	१५०	४९	७७	७	२	४	३	१	७

इसलिए कोदालिया के केवल ३६ ८ प्रति शत परिवार ही अपने आठ और बीस वर्ष के बीच की आयुवाले बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, कामनारा में पाँच और सोलह वर्ष के बीच के बच्चों को पढ़ने भेजने की अवस्था में परिवारों का प्रतिशत ५१ है। घाटमपुर के ८९ घरों में पाँच से सोलह वर्ष तक के आयुवाले बच्चे हैं। उनमें से केवल ४२ परिवार ही उन्हें स्कूल भेजने में समर्थ हैं। घाटमपुर के लोगों के दृष्टिकोण यानी रुख के सम्बन्ध में श्री मेन गुप्त लिखते हैं “वे परिवार जिनमें ५-१६ वर्ष के आयु-वर्ग में आनेवाले बच्चे हैं और अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते सम्भवतः इतने गरीब हैं कि बच्चों की शिक्षा पर होंनेवाला मामूली खर्च भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कालेज पढ़ने जानेवाले युवक के अभिभावकों को उसकी शिक्षा के लिए आन्दाजन ६०० रुपये वार्षिक खर्च करना पड़ता है।

“गौव के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता के प्रति परिपूर्णतः मजबूत हैं। यहाँ तक कि १९१६ में उन्होंने खुद ने पहल करके तत्कालीन जमींदार के स्थानीय अहलकार के नोहरे में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। सन् १९२५ में विद्यालय अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया। स्कूल की इमारत गौव के ग्वालों और मुसलमानों द्वारा दान में दी गयी जमीन पर बनायी गयी। मकान ग्रामीणों द्वारा एकत्रित चन्दे से बनाया गया था। गौव के सादगोपो ने छत के लिए आवश्यक सी आय चादरे दी और दरवाजे तथा खिड़कियों के चौखट-किवाडों की भी पूर्ति की। स्कूल को जिला स्कूल मण्डल ने अपने अन्तर्गत लिया उससे पहले उसका आवर्ती खर्च किसी हद तक स्कूल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य वहन करते थे।

“पोरबाजार में एक जूनियर हाय स्कूल और बेलमुडी में एक हाय स्कूल है।

वे प्रौढ भी साक्षर होने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिन्हें अपने बचपन में स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन गौव में प्रौढ शिक्षा केन्द्र नहीं है।”

सर्वेक्षणों ने वर्तमान संचार व्यवस्था की खामी को

सामने ला कर रख दिया है। कोदालिया के अट्ठाईस परिवार अब्बार पढ़ते हैं, जबकि १२ प्रति शत रेडियो सुनते हैं। कामनारा के १५० घरों में से ११ ही अब्बार मँगवाते हैं और पढ़ते हैं। केवल दो घरों में रेडियो ट्रांजिस्टर और एक में ग्रामोफोन है। घाटमपुर के १५ परिवारों में समाचार-पत्र पढ़े जाते हैं और छ परिवारों के पास रेडियो हैं (तथा छ अन्य परिवार नियमित रूप से रेडियो सुनते हैं)।

कोदालिया के अधिकांश कर्मकारों, बौरियों और बागडियों को यह नहीं मालूम है कि छूआछूत कानूनन मिटा दिया गया है। कामनारा में केवल ५५ घरों के प्रधानों को ही इस बात का ज्ञान है कि अन्तर्जातीय विवाह की कानूनन इजाजत है, जबकि इस बात की जानकारी मात्र ३८ परिवारों को ही है कि छूआछूत कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया है। घाटमपुर में तो स्थिति और भी खराब है। वहाँ के केवल १७ परिवार ही यह जानते हैं कि अन्तर्जातीय विवाह करने की कानूनी तौर पर इजाजत है।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की दिशा में विस्तृत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। निस्सन्देह शिक्षित व्यक्तियों की सख्या में वृद्धि होने के साथ यह समस्या सहल होगी, लेकिन अनेक परिवारों के अपने बच्चों को स्कूल भेजने का खर्च बर्दाश्त करने में असमर्थ होने की वजह से असाक्षरता मिटाने में जल्दी ही सफलता नहीं मिलनेवाली है। और फिर, प्रौढ असाक्षरता भी कोई मामूली समस्या नहीं है। इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि सबसे पहले सभी स्थानों पर नि शुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाय, प्रौढ शिक्षा वर्ग और रेडियो श्रव्य केन्द्र खोले जायें। तिस पर भी, यदि भूतकालीन अनुभव को मार्गदर्शक माना जाय तो इन सब बातों से लाभ उठाने के लिए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों को तैयार करने की दिशा में हो सकता है कि मात्र शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार भर कर देना ही पर्याप्त न हो। अनेक परिवारों के लिए छोटे-मोटे कामों में मदद देनेवाले अपने बच्चों

को स्कूल भेजना कठिन हो सकता है, और फिर कई परिवारों में पर्याप्त कपड़ों का अभाव बच्चों को पढ़ने भेजने के रास्ते में एक बाधा है।

असमानता और तंगी

सर्वेक्षणों से गाँवों में असमानता और तंगी की मौजूदगी की पुष्टि होती है—जो कि ग्राम्य जीवन की आदर्शवादिता को बहुत कुछ झुठलाती है। असमानता न केवल इस बात में प्रतिबिम्बित होती है कि लोग कैसे घरों में रहते हैं अथवा कैसे आभूषण पहनते हैं, बल्कि घरों की जमीन के स्वामित्व में भी इसकी प्रति-छाया मिलती है। उदाहरणार्थ, कामनारा में ५१ परिवारों के घर दूसरों की जमीन पर हैं, जबकि घाटमपुर में ऐसे परिवारों की संख्या ३९ है, जैसा कि निम्न तालिका से प्रकट है

कामनारा और घाटमपुर में घर की जमीन पर स्वामित्व

घर का क्षेत्रफल	परिवार संख्या	
	कमनारा	घाटमपुर
५ कट्ठो तक	५५	४९
६ से १० कट्ठो तक	२९	२९
११ से १५ कट्ठो तक	३	४
१६ कट्ठो से १ बीघा तक	२	१५
१ बीघा से अधिक	१	१४
इजमाली एस्टेट (संयुक्त स्वामित्व)	९	—
दूसरों की जमीन पर रहनेवाले	५१	३९
योग	१५०	१५०

कृष्य भूमि के मामले में भी इसी प्रकार की असमानता दृष्टव्य है। घाटमपुर में ७८ परिवारों के पास ही कृष्य भूमि है, कामनारा के १५० परिवारों में से केवल ७२ के पास ही कृष्य भूमि है।

घाटमपुर गाँव के सम्बन्ध में श्री सेन गुप्त लिखते हैं, “ग्राम समाज ऐक्यता से बहुत दूर है। गाँव में कई गुट हैं। गुटों अथवा फिरका-परस्ती के लिए केवल जाति अथवा समुदाय ही जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि मुसलमानों तथा सादगोपों और ग्वालों में भी एक से अधिक गुट हैं।”—पृष्ठ २९।

इन सर्वेक्षणों के अन्तर्गत आनेवाले गाँवों के लोगों में यद्यपि अपने वर्तमान काम-धंधों के प्रति कुछ असन्तोष है तथापि, परिवर्तन के लिए किसी निश्चित इच्छा का प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होता। श्री सेन गुप्त लिखते हैं कि कमनारा में “१५० परिवारों में से ९७ से मुलाकात की गयी और वे अपनी मौजूदा अवस्था से सन्तुष्ट हैं। जब तक उनके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं होता यह अपेक्षा करना व्यर्थ होगा कि वे अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए स्वयम् कोशिश करेंगे।”—पृष्ठ २९। हाँ, इसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात भी नहीं है। परिवर्तनार्थ इच्छा के लिए आगे आने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक प्रधान रूप से अनपढ़ समाज में लोगों के विचार और उनकी कल्पना स्पष्टतः सीमित ही होगी, उन्हें परिवर्तन के लिए इच्छा न होने—जोकि ज्ञान अथवा इस आश्वासन पर ही आगे आती है कि कोई बेहतर चीज सम्भव है—के लिए दोषी ठहराना गलत होगा। जिस हद तक गाँवों में परिवर्तन के लिए इच्छा जागृत नहीं हुई है उस हद तक स्वयम् आयोजन का एक प्रधान पक्ष असफल रहा है, क्योंकि आयोजन खुद ही परिवर्तन की आवश्यकता का द्योतक है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि परिवर्तन की आवश्यकता तथा साथ ही उसकी सम्भाव्यताओं और इस प्रकार का परिवर्तन व्यवहार में लाने के लिए कार्यक्रमों पर जोर देते हुए ग्रामीणों में उक्त विचार भरने की कार्यवाई अथवा कार्यक्रम का सृजन किया जाय, उसे चलाया जाय।

अन्त में सर्वेक्षण के प्रवर्तक धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने देहाती क्षेत्रों के वास्तविक जीवन सम्बन्धी भरपूर सहायक जानकारी उपलब्ध करवायी है। जनगणना आयुक्त श्री अशोक मित्र हमें बताते हैं कि “सम्भवतः प्रथम बार किसी देश में इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है और वह भी निशुल्क सेवा के रूप में।” जाँच-कर्ताओं, फोटोग्राफरों तथा लेखकों ने अपने काम के द्वारा, और जनगणना आयुक्त ने भी इनके प्रकाशन की योजना स्वीकृत कर, सभी की ओर से आभार अर्जित किया है। आशा है कि भविष्य में तैयार किये जानेवाले मोनोग्राफों में इस बात के अध्ययन पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा कि ‘एस्टेट एक्वीजीशन एक्ट’ तथा भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है।

पुस्तक समीक्षा

विकास के लिए प्रशासन

एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड इकनॉमिक डेवल-
पमेण्ट इन इण्डिया: राल्फ ब्रेबाण्टी और जॉसेफ
जे स्पेंगलर द्वारा सम्पादित, ड्यूक विश्वविद्यालय प्रेस,
इरहम, १९६३, पृष्ठ ३१२; मूल्य ७५० डालर।
इस सकलन में, जिसमें प्रग्यान अमरीकी तथा भागनीय
समाजशास्त्रियों के लेख सम्मिलित हैं, भारत में आर्थिक
विकास तथा प्रशासन के सबंधों का विवेचन है। इस ग्रन्थ
में प्रकाशित १० में से ४ लेख १९६० के बमन में ड्यूक
विश्वविद्यालय के राष्ट्र मंडलीय अध्ययन केन्द्र की
संयुक्त विचार-गोष्ठी की बैठकों में प्रस्तुत किये गये थे
और उनकी रचना प्रोफेसर मित्र, मैलेनबॉम, मोवनी
और पार्क ने की थी। अन्य छ लेख विचार-गोष्ठी
के बाद के महीनों में प्रोफेसर ब्रेबाण्टी, जगोटा, टिलमैन
स्पेंगलर और टिकर द्वारा लिख गये थे। सम्पादकों ने
भूमिका में लिखा है कि यद्यपि प्रत्येक निबन्ध अलग से
लिखा गया है, तथापि सभी आर्थिक तथा प्रशासनिक
क्षेत्रों में विकास की समस्या पर प्रकाश डालते हैं।

ड्यूक विश्वविद्यालय के प्राफेसर राल्फ ब्रेबाण्टी जो—
सम्पादक द्वय में से एक हैं—का प्रारम्भिक लेख 'भारत में
नौकरशाही सुधार' (ब्यूरोक्रेटिक रिफार्म इन इंडिया)
है जिसमें उन्होंने यह अभिव्यक्ति की है कि सन् १९४७
से भारत में प्रशासनिक सुधार का कार्यक्रम सुचारु रूप

में तैयार किया गया और उसमें व्यवस्था, 'मन्तुलन और
प्राथमिकताओं के सुनियोजन की दृढ़ भावना उल्लेखनीय
है। लेख के प्रथम भाग में भारत में प्रशासनिक विकास
की सरसरी तौर पर समीक्षा की गयी है, जो उपयुक्त
परिकल्पना को न्यायपूर्ण ठहराती हुई प्रतीत होती है।
प्रोफेसर ब्रेबाण्टी का विचार यह है कि प्रशासनिक
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत यह
व्यवस्थित और विवेकपूर्ण संयोजन बहुत हद तक दृढ़
पारम्परिक बौद्धिकता, स्वतंत्र भाव तथा भारतीय नागरिक
सेवाओं पर गर्व से सभ्य हो सका है। इनमें से पहले
गुण का, जो हिन्दू समाज में प्राप्त हुआ तथा ब्रिटिश
राज द्वारा कायम रखा गया, १९४७ के बाद के उच्च
नौकरशाही के विकास में अपना महत्व है।

लेख के दूसरे भाग में यह प्रदर्शित करने के लिए
प्रमाण उपस्थित करने की कोशिश की गयी है कि बौद्धि-
कता आई सी एस की परम्परा का प्रमाण चिन्ह थी।
तीसरे भाग में एक परिकल्पनात्मक विरोध का निर्माण
करके नौकरशाही सुधार के लिए कूटतार्किक नौकरशाही—
बौद्धिकता-युक्त तंत्र—को-संगत सिद्ध करने का प्रयास
किया गया है। इसमें उन राष्ट्रों की द्विविधा की
विस्तृत व्याख्या भी सम्मिलित है जो विदेशी सरकारों
से बहुत बड़ी मात्रा में सहायता ले रहे हैं। इस विश्लेषण

का तात्पर्य है उन कमजोरियों को दिखाना, जिनको भारत ने ढाल दिया है। “यह ढालना बौद्धिकता तथा व्यवस्था की सम्मानित परम्परा के कारण सम्भव हो सका है, जो अनिच्छापूर्वक हानिकारक परिवर्तन का प्रतिकार करते हुए प्रबल बौद्धिक अभिमान के अनुकूल परिवर्तनों को स्वीकार करती है। भारत सार्वजनिक प्रशासन में किसी विदेशी सरकार से बड़ी मात्रा में तकनीकी सहायता नहीं प्राप्त करते हुए अपनी नौकर-शाही को नियंत्रित तथा निर्देशित कर सका है।”

चौथे भाग में भारतीय नागरिक सेवाओं (इंडियन सिविल सर्विसेज) के परिवर्तन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इसमें यह बात रखी गयी है कि ऐसा परिवर्तन, अधिकतर परिवर्तन के चुनाव-तरीकों में भेदभाव करने की इसकी क्षमता के कारण, सार्वजनिक प्रशासनिक खन्तों के अतिरेक को ढालने में सफल रहा। “भारतीय प्रशासनिक सेवा में इसका विकास अप्रदर्शित किन्तु व्यवस्थित रहा, भारतीय प्रभुत्व तथा नियंत्रण वर्चस्व होने के कारण यह क्षणिक आधुनिकता का त्याग करने तथा भारतीय समाज की विशिष्ट परम्पराओं और मागों का समजन करने में सफल रहा।”

प्रोफेसर ब्रेबाण्टी अपने अनुभवों को प्रभावित करने-वाली बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त की जानकारी प्रदान करते हैं। वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी जानकारी वास्तव में हुए परिवर्तनों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह परिवर्तन की कुल योजनाओं पर आधारित है। “निसंदेह सोद्देश्य आयोजन तथा कार्यान्वयन में विशाल अन्तर है। सचमुच भारत के समक्ष अब भी भयानक प्रशासनिक समस्याएँ हैं, जिनमें भ्रष्टाचार और अक्षता, ग्रामीण सुधार और प्रशासन में विनाशकारी सांस्कृतिक शक्तियाँ मुख्य नहीं हैं।”

अगले लेख ‘भारत में सार्वजनिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण’ (ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन इंडिया) में मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के प्रोफेसर एस पी जगोटा ने भारत में राज्य कार्य के परिवर्तित

सदर्भ में भारत के लिए आवश्यक सार्वजनिक कर्मचारियों के प्रकार तथा उसके कारण उठे प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। प्रथम पच वर्षीय योजना में सफल आयोजन की आवश्यक शर्तों में एक यह भी उल्लिखित है—“आवश्यक योग्यता तथा गुण से युक्त कर्मचारी सहित एक कार्यक्षम, प्रशासनिक संगठन।” इसकी विस्तृत व्याख्या यह हो सकती है कि उच्चतर नागरिक सेवा को देश में जो कुछ हो रहा है उसका मूलभूत ज्ञान, तत्कालीन सामाजिक क्रान्ति के सिद्धान्तों तथा कार्यों और अन्य स्थानों की तुलनात्मक क्रान्तियों के इतिहास की जानाकारी अवश्य होनी चाहिए तथा उनमें सार्वजनिक सेवाओं की अनेक मागों को पूरा करने के लिए उचित दृष्टिकोण और व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। उचित दृष्टिकोण तथा व्यवहार में ईमानदारी, विनम्रता, सार्वजनिक सेवा के लिए सोद्देश्य उत्साह और कार्य के अनुकूल अपने को ढालने की क्षमता—जिसकी अपेक्षा सार्वजनिक कर्मचारी से की जाती है,—शामिल है। प्रशासनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थ वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी योग्यता और गुणवाले कर्मचारी तैयार करने के लिए किये जा रहे प्रयासों की प्रोफेसर जगोटा ने सावधानी तथा समझ के साथ समीक्षा की है। उनका मत है कि यद्यपि कमियाँ हो सकती हैं और अधिक उन्नति तथा नवीनीकरण की सम्भावना भी, तथापि वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भी मालूम पड़ता है। कार्यक्रमों की प्रगति अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई जटिल आवश्यकताओं के साथ होती रही है। नवीन उच्च स्तर पर विशिष्टता प्राप्त कार्यक्रम के साथ देश में बदलती हुई स्थितियों की आवश्यकताओं से समजित नयी संस्थाएँ विकसित हुई हैं।

प्रोफेसर जगोटा ने सवैधानिक आयोजन के कुछ पहलुओं (सम एसपेक्ट्स ऑफ कान्स्टीट्यूशनल प्लानिंग) पर एक दूसरा लेख लिखा है। उन्होंने समापन किया है कि भारत में आयोजन, जो एक सघीय ससदीय जनतंत्र के रूप में चलाया जा रहा है, राज्य और तेजी से आर्थिक

तथा सामाजिक विकास के हित में परिवर्तित हुआ है। आयोजन तंत्र और परिचालन, जा न तो सर्वप्रधान और न किसी विधि के अन्तर्गत स्थापित होता है, द्वारा नयी समस्याएँ गठित हुई हैं, जिनमें राजनीतिक समस्याओं की क्रिया, सरकारी तंत्र, आय-व्यय का लेवा-जोखा करने के तरीके, सघ और राज्य के सन्ध, वित्त आयोग के कार्य आदि प्रभावित हुए हैं। आयोजन में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के संगठन और सरकार तथा समद, में उनके सवन्धों के विषय में समस्याएँ खड़ी हो गयी हैं। इन समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः फल-मूलक रहा और परिणाम स्वरूप उचित समस्याएँ और तौर-तरीके प्रकट हो रहे हैं। इन विस्तृत प्रभावों के बावजूद आयोजन ने सर्वप्रधान स्वरूप के महत्वपूर्ण पहलुओं को विनष्ट नहीं किया है। "देश का स्वरूप मौलिक तौर पर मधीय है और वह इस हद तक कि यह टीका होती है कि उसमें राष्ट्रीय एकता में बाधा पड़ती है और इसलिए कुशल प्रशासन तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए देश में एकात्मक सरकार आवश्यक है।"

लन्दन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ह्यूज टिकर ने एक लेख 'विकास के स्वरूप में ग्राम' (दि विलेज इन दि फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेण्ट) में भारत के गाँवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। उनका दृष्टिकोण एक इतिहास-कार अथवा राजनीति-वेत्ता का है जिसमें व्यापक प्रमाणों के जरिये परिकल्पना की गयी है, न कि एक मानवशास्त्री का, जो कि एक सीमित क्षेत्र के विस्तृत ज्ञान से निर्णय तक पहुँचता है। प्रोफेसर टिकर ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि ग्राम स्तरीय जनतंत्र के दर्शन को सफल होना है तो यह बड़ा ही आवश्यक है कि सामुदायिक विकास आन्दोलन ग्राम स्तर पर शक्ति की सन्धि दशिये। वर्तमान पुष्टियों से व्यक्त होता है कि प्रवृत्ति ठीक उल्टे पिरामिड की-सी रही है, जिसकी जयप्रकाश नारायण ने भारत में ससदीय सरकार की असफलता के रूप में निन्दा की है। तथापि, प्रोफेसर टिकर स्वयम् एक स्थान पर स्वीकार करते हैं कि यदि भारत

स्वेच्छिक सहयोग से गठित, समान नागरिक के रूप में सामान्य लोगों के साथ-साथ कार्य करने तथा जन सम्पत्ति पर आधारित समाज रचना के निर्माण के अपने घोषित उद्देश्य के प्रति सच होना चाहता है तो इस दिशा में पचायत राज एक बड़ा कदम है।

मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड पार्क का लेख है— 'भारत के जिलों में प्रशासनिक सहकार और आर्थिक विकास' (एडमिनिस्ट्रेटिव कोआपरेशन एण्ड इकनॉमिक डेवलपमेण्ट इन दि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया)। वे जिलों में आर्थिक विकास की सरकारी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और प्रशासन के ग्रामीण तथा जिला स्तर पर हाल के विधि-निर्माण तथा प्राकृतिक प्रस्तावों की समीक्षा करते हैं। "जब तक किसी को यह नहीं मालूम कि कब तथा कैसे किस को क्या करना है, और कब तथा कैसे रसद प्राप्त की जाती है और किससे तथा किस प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति स्थापित होती है और इन शक्ति केन्द्रों में कहाँ अन्तिम निर्णय-कर्ता निहित है, तब तक किसी प्रकार की अच्छी योजना का परिणाम प्रभावशाली ढंग से क्रियात्मक नहीं हो सकता।" यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रशासन और उसका गठन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण तत्व है।

पेन्सिलवानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलफ्रेड मैलनबॉम ने अपने लेख 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था में नेतृत्व का प्रश्न' (लीडरशिप टास्क इन इंडियाज इकनॉमी) में भारत के आर्थिक विकास में सन्निहित राजनीतिक नेतृत्व की कठिनाइयों की विवेचना की है। उनका विचार है कि भारतीय सामाजिक विश्लेषण का सम्पूर्ण ढांचा भारत के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के अपेक्षाकृत अल्प विकसित चरण के लिए बहुत ही कूट तार्किक है। वे भारत की योजनाएँ बनानेवालों का आह्वान करते हैं कि उन्हें अधिक सम्पन्न देशों (राज्यों) के लिए अनुकूल उन्नत सिद्धान्तों और तकनीकों पर अधिक निर्भर न रह कर अल्प विकसित भारत के अपने ही अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि अधिक

यथार्थ रूप में योजनाएँ बनायी जा सकें। योजना बनाने और उसको पूरा करने के बीच की दूरी की ओर सकेत करते हुए प्रोफेसर मैलनबॉम लिखते हैं कि योजना के कार्यान्वय की कमी के लिए प्रशासनिक संगठन की असफलता की अपेक्षा यथार्थ योजना अधिक उत्तरदायी है। कार्यान्वय के लिए योजना का कार्यान्वित करने योग्य होना अत्यावश्यक है।

टुलन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राबर्ट टिलमैन ने 'भारत के आर्थिक विकास में जाति-प्रभाव' (इन्फ्लू-यन्स ऑफ कास्ट इन इंडियन इकनॉमिक डेवलपमेण्ट) लेख लिखा है। उनका लेख इस मान्यता पर आधारित है कि आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए सामाजिक गतिशीलता आवश्यक शर्त है, प्राचीन प्रथा के अनुसार जातिगत रूप में मूल्यांकन सामाजिक गतिशीलता का विरोधी है और इसलिए भारत के आर्थिक विकास की सफलता कुछ अंश में परम्परा की निश्चलता और परिवर्तन की शक्तियों की अन्त क्रिया के प्रतिफल पर निर्भर करती है। प्रोफेसर टिलमैन समापन करते हैं कि परम्परागत जातीय विचार-धारा से अलग वातावरण में जातिवादी भारतीयों की प्रतिक्रिया यह बताती है कि परिवर्तन

की अतिक्रमणकारी शक्तियों का देश की सामाजिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है।

सकलन में ऊपर वर्णित लेख प्रमुख हैं। शेष तीन लेख अधिक विशिष्ट रूप में आर्थिक समस्याओं से संबंधित हैं। ड्यूक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे जे स्पेग्लर कौटिल्य अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं। गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स के प्रोफेसर सोवनी अर्थशास्त्रीय तौर पर उन गैर-आर्थिक तथ्यों की व्याख्या करते हैं जो भारत की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डाल रहे हैं। पुनर्गठन और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (इन्टरनेशनल बैंक ऑफ रिकस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेण्ट) के श्री अशोक मित्र कृषि पर कर-भार और आर्थिक विकास में उसके सबधों की व्याख्या करते हैं।

सम्पूर्णतः पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गयी है और सम्पादक द्वय अभिनन्दनीय हैं कि उन्होंने एक स्थान पर कुछ ऐसे उपयोगी लेखों का संग्रह किया है, जिनसे भारत में आर्थिक विकास और प्रशासन का अध्ययन करनेवाले भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थी पर्याप्त लाभ उठा सकेंगे तथा उसे गहरी रुचि के साथ पढ़ेंगे।

नयी दिल्ली १० सितम्बर १९९३ —सुभाष चन्द्र मेहता

ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने और द्रुत गति से बढ़ रही शहरी आबादी को खाद्यान्न तथा कच्ची सामग्री प्रदान करने, दोनों ही दृष्टियों से स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन में सुस्थिर अर्थात् ठोस वृद्धि करना परमावश्यक है। विकास के स्थूल लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसन्धान परिषद का मत है कि १९५६-७५ के दौरान विशुद्ध कृषि उत्पादन दुगुना हो जाना चाहिए अर्थात् प्रति वर्ष औसतन पाँच प्रति शत वृद्धि होनी चाहिए, राष्ट्रीय आयोजन में भी प्रायः यही गति मानी गयी है।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात : नेशनल
कॉउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।



मैंने कई लेख पढ़े। भारत की ग्रामीण अवस्था को यथा सम्भव सच्चे रूप में प्रस्तुत करना अच्छी बात है। इस दृष्टि से कई लेख स्पष्ट और सगत हैं, जैसे, सम्पादकीय और श्री उ न डेबर का लेख तथा उसी तरह कुछ हद तक श्री सुन्दरम् का 'यथार्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता' और श्री मुकर्जी का 'गावों के लिए ऋण की व्यवस्था' भी मूल्यवान हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी लेख हैं, जो कि मेरी दृष्टि से निश्चय ही कम यथार्थपूर्ण हैं। उनमें वे लेख हैं जिनमें ग्रामीण समाज के गरीब और अमीर लोगों के बीच का कोई अन्तर नहीं बताया गया है तथा फलतः ग्राम समाज को बहुत-कुछ सम्पूर्ण दृष्टि से देखा गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण बेकारी को दूर करने की समस्याओं को भूमि वितरण और ग्राम समाज के अन्दर शक्ति के स्वरूप की समस्या से अलग करके नहीं देखा जा सकता, जैसा कि कई लेखों में अच्छी तरह बताया गया है।

व्यक्तिगत रूप से मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि अभी काफी समय तक ग्रामीण उद्योग बहु-संख्यक भूमिहीन मजदूरों और किसानों तथा छोटे-छोटे किसानों को अतिरिक्त रोजगारी देने व आय कराने के लिए अनिवार्य होंगे। मैं 'खादी' को भारत की ग्रामीण समस्या को हल करने का साधन नहीं मानता और इस मामले में आपके कई लेखों से मेरा मतभेद हो सकता है। यह ग्राम समाज की बीमारियों को दूर करने की दवा नहीं है—अधिक से अधिक यह उपशमक है। मेरी दृष्टि से मूल बीमारी है गावों में छोटी संख्यावाले बड़े भूस्वामियों की स्थायी शक्ति। इस 'शक्तिशाली वर्ग' की शक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करने और कृषि विकास के प्रयासों की मदद से ही सरकार की भारी उद्योग और गृह उद्योग क्षेत्र में बड़े पैमाने की योजनाएँ सफल हो सकेंगी।

एम्सटर्डम विश्वविद्यालय
१२ दिसम्बर १९६३

—प्रो डब्ल्यू एफ. बर्थिस

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए 'ग्रामोदय,' इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५९ से प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल - एसोसिएटेड एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ५०५, तारदेव, आर्थर रोड, बम्बई-३४।
वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ नये पैसे।

खादी ग्रामोद्योग : १९६२-६३ के विशिष्ट लेख

प्रभावशाली प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था	-उछरगराय न. बेबर
शहरीकरण और ग्रामोद्योग	-वैकुण्ठ ल. मेहता
आर्थिक विकास में मानवीय पहलू	-विजयेन्द्र कस्तूरी रं. व. राव
बैंक चित्त और औद्योगिक सहकार.	-ब्रह्मदेव मुकर्जी
ग्रामीण औद्योगीकरण में शिक्षा का महत्व	-कन्दस्वामी अरुणाचलम्
हमारा अगला कदम	-ध्वजा प्रसाद साहू
व्यवस्था खर्च या सेवा खर्च.	-द्वाराकानाथ वि. लेले
कृषि-विषयक नीति के लक्ष्य	-तरलोक सिंह
ग्रामोद्योगों का भावी विकास	-त्रिभुवन नारायण सिंह
ग्रामोद्योगों का सघन विकास	-दया किसन मल्होत्रा
ग्रामीण औद्योगीकरण	-प. सामु लोकनाथन्
भारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक स्वरूप	-मुभाष चन्द्र सरकार
गोंवो का बदलता रूप	-चित्तप्रिय मुखर्जी
भारत की ग्रामीण आबादी	-शिख प्रसाद चटर्जी
घरखे का भविष्य	-मनमोहन चौधरी
ग्रामोद्योगों के विकास में सहकारी समितियों की भूमिका	-देवचंद अ. शाह
असम की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	-भवानन्द डेका
मैसूर राज्य की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	-डो. स. नंजुडप्पा
महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	-वसन्त द. देशपाण्डे और मधुकर वि. नामजोशी
गुजरात की कृषि अर्थ-व्यवस्था	-रामदास फिरोरदास अमीन
ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी प्रेरणा	-अल्फ्रेड सॅम्पुजल

वार्षिक शुल्क : २ रुपये ५० नये पैसे ● एक प्रति : २५ नये पैसे

प्राप्ति स्थल

खादी और ग्रामोद्योग कमिशन

ग्रामोदय, बम्बई-५६

* खादी ग्रामोद्योग (वार्षिकांक) १९६३ *

विषय सूची

दशम वर्ष

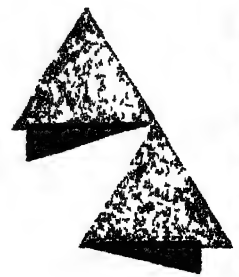
भारत में सामाजिक और आर्थिक विपन्नताओं का स्वरूप	-उत्तरंगराय न. टेबर
आयोजन का गांधीवादी दृष्टिकोण	-वैकुण्ठ ल. मेहता
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के चन्द पहलू	-मोरारजी देसाई
शैक्षणिक प्रगति तथा औद्योगीकरण	-कन्दस्वामी अरुणाचलम्
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग कार्यक्रम	-त्रिभुवन नारायण सिंह
गाँवों के लिए ऋण की व्यवस्था	-ब्रह्मदेव मुकर्जी
हमारी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर खादी का प्रभाव	-अरुण चन्द्र गुहा
खादी 'कस ओर'?	-ध्वजा प्रसाद साहू
खादी का भविष्य	-रामकृष्णराव कृ. पाटिल
खादी का मिशन	-झवेरभाई पटेल
अम्बर की शक्यता	-शंकरलाल बैकर
यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक	-जोसेफ दु. सुन्दरम्
गत पन्द्रह वर्ष में रोजगारी व बेरोजगारी	-मगवन्त नागेश दातार
भारत में पूँजी संचयन और निवेश	-अमृतलाल दत्त
आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामोद्योग	-बहराम होरमसजी मेहता
कृषिक अनुसंधान और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	-अब्दुर रहीम खॉ
हमारे हड्डी स्रोत	-शिशिर कुमार बराट
ग्रामीण रोजगारी और योजना	-चित्तीप्रिय मुखर्जी
ग्रामीण औद्योगीकरण में वैज्ञानिकों और आभयताओं की भूमिका	-मंजेश्वर सदाशिव राव
भारत पर नयी दृष्टि	-गौरी शंकर रायचौधरी
स्त्री शिक्षा की समस्याएँ	-श्रीपति श्रीदेवी
बंगाल में शहरीकरण के कुछ पहलू	-मीरा गुहा
मितव्ययी तिलहन एकत्रण की ओर	-पु. वि. श्रीकण्ठ राव
समृद्धि की दुविधा	-सुभाष चन्द्र सरकार
पुस्तक समीक्षा	

दशम वर्ष
पंचम अंक
१९६४
फरवरी



रवार्ड

ग्रामोद्याग



खादी और ग्रामोद्योग कमीशन

- खादी और ग्रामोद्योग कमीशन एक विधिविहित सस्था है, जिसकी स्थापना ससद के अधिनियम (१९५६ के ६१ वे) के मुताबिक अप्रैल १९५७ में हुई। इसका काम है अपने अन्तर्गत चलनेवाले १५ ग्रामोद्योगों के लिए योजना बनाना, संगठन करना तथा उनके विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। स्थापना होने पर इसने भूतपूर्व अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का कार्य अपने हाथ में लिया। कमीशन के पांच सदस्य हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव हैं। इसके सलाहकारी खादी और ग्रामोद्योग मण्डल में ४८ सदस्य हैं। कमीशन साधारण-तया इस सलाहकारी मण्डल की राय से कार्य करता है।
- कमीशन के अन्तर्गत खादी के अतिरिक्त ये ग्रामोद्योग हैं अनाज तथा दाल प्रशोधन, तेल घानी, ग्रामीण चर्म, कुटीर दियासलाई, गुड-खाण्डसारी, ताड़-गुड, अखाद्य तेल तथा साबुन, हाथ कागज, ग्रामीण कुम्हारी, मधुमक्खी-मालन, रेशा, बढईगीरी तथा लोहारगीरी, खाद तथा मिथेन गैस का उत्पादन व उपयोग और चूना पत्थर तथा उसके उत्पादन।
- कमीशन के कार्यक्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन का कार्य स्वयम् करने, उनके लिए सहायता तथा प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त ये कार्य भी मुख्य रूप से सम्मिलित हैं खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन-कार्य में लगे कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उन्हें अपनी सहकारी समितियों बनाने में प्रोत्साहन देना।
- कमीशन खादी तथा ग्रामोद्योगी वस्तुओं के उत्पादकों को सप्लाई करने के लिए कच्ची सामग्री तथा औजारों का सग्रह भी करता है। खादी तथा ग्रामोद्योगी उत्पादनों के बेचने की व्यवस्था करने का कार्य भी कमीशन के जिम्मे है।
- कमीशन को खादी तथा ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाली प्रविधियों के विषय में अनुसंधान कराने तथा उसे प्रोत्साहन देने और खादी तथा ग्रामोद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए सुविधाएँ प्रस्तुत करने का कार्य भी सौंपा गया है।

दशम वर्ष • फरवरी १९६४ • पंचम अंक



राष्ट्रीय एकता का आर्थिक पक्ष	-जवाहरलाल नेहरू	३३३
अहिंसा के सामाजिक निहितार्थ	-उत्तरगुप्त न. देबर	३३६
खादी और अर्थ-व्यवस्था	-वैकुण्ठ ल. मेहता	३४६
हाथ कागज उद्योग में निर्यात पत्र का उत्पादन	-शदाशिव राव और बालचन्द्र मा. अग्नीकर	३४०
ग्रामीण औद्योगीकरण के लाभ	-भारत भूषण कशाल	३४४
मैसूर के गावों में प्रचलित काम-धंधे	-वन्दार वेङ्कप शेटी	३४९
पंचायत राज और सामुदायिक विकास	-नफीस बेग	३६२
खादी-ग्रामोद्योग तथा उनकी स्फीति निवारक क्षमता	-श्रीमनाथन नायर	३६५
पश्चिम बंगाल के कुटीर शिल्प	-आशीश कुमार बसु	३७३
पंचायतों के साधन-स्रोत		३७५
ग्राम सफाई	-जगेश्वर गोपाल श्रीखण्डे	३८७
गुड और खाण्डसारी उद्योग	-दीना नाथ दुबे	३८९
पाठकों के विचार		३९१

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोद्योग', इलाहाबाद, बम्बई-५६ से मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थ शास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोद्योग', इलाहाबाद रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। टेलिफोन नं. ५७१४५२।

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ रुपये। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए अतिरिक्त एकाउण्ट्स ऑफिसर (कैश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोद्योग', इलाहाबाद रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६।

इस अंक के लेखक

जवाहरलाल नेहरू	—भारत के प्रधान मंत्री।
उछरगराय नवलशकर डेबर	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष।
वंकुण्ठ लल्लूभाई मेहता	—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य।
मजेश्वर सदाशिव राव	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की ग्रामीण इजीनियरिंग शाखा के निर्देशक।
बालचन्द्र मार्टी अग्शीकर	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला के भूतपूर्व रासायनिक तकनीकल सहायक।
भारत भूषण कसाल	—गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) की एम एम कालेज में वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष।
खन्दार बैक्कप्प शेटी	—शिमोगा (मैसूर राज्य) में परियोजना मूल्यांकन अधिकारी।
नफीस बेग	—अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में रिसर्च फेलो।
चेम्पकमडम परमेश्वरन पिलै सोमनाथन नायर	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के प्रचार निर्देशालय में उप-सम्पादक।
जागेश्वर गोपाल श्रीखण्डे	—सेवाग्राम (वर्धा) स्थित खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला के भूतपूर्व निर्देशक।
दीना नाथ बुबे	—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के प्रचार अधीक्षक।
आशीश कुमार बसु	—अखिल भारत दस्तकारी मण्डल के कलकत्ता स्थित कनिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी।

राष्ट्रीय एकता का आर्थिक पक्ष*

जवाहरलाल नेहरू

बुनियादी उद्योगों, बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाओं आदि जैसी देश को आगे बढ़ानेवाली बुनियादी बातों पर जोर देने के साथ ही साथ हमें निचले तबके के लोगों—जिनमें अधिकांश हमारे किसान और ग्रामीण कारीगर आते हैं—को तुरन्त लाभ पहुँचानेवाली चीजों पर भी जोर देना होगा। खेती, पशु-पालन, ग्राम और लघु उद्योगों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने यानी उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ किया जाय, तो उससे तुरन्त निचले तबके के लोगों की आमदनी बढ़ेगी।

राष्ट्रीय एकता का एक दूसरा पक्ष और है। और, हमें यह मान लेना चाहिए कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह पक्ष है हमारी अर्थ-व्यवस्था का विकास। यदि कोई राष्ट्र अपनी विकट आर्थिक समस्याओं को सन्तोषप्रद रूप से हल नहीं करता है तो वे बड़ से बड़तर होती चली जाती हैं और ऐसी सामाजिक अवस्थाएँ खड़ी कर देती हैं, जिनका एकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एकता की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ योजना आयोग है। उसने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अनेक कि न समस्याएँ आज भी हमारे सामने हैं। तरक्की करने और हमारी समस्याओं को रफ़्तार-रफ़्तार हल करने के लिए हम केवल आधार ही बना पाये हैं। योजना आयोग के सामने इस गोष्ठी के अध्यक्ष श्री डेबरभाई ने जो 'नोट' पेश किया है, उसमें उन्होंने ऐसे चन्द महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं।

कमजोर वर्गों की समस्या

उद्योग और खेती के क्षेत्र में आर्थिक विकास करने की साधारण समस्याओं के अलावा हमारे सामने एक विशेष समस्या यह है कि देश के कमजोर वर्गों का स्तर ऊपर कैसे उठाया जाय। समाज के कमजोर और निचले तबके

के लोगों की तरक्की कोई खास अच्छी नहीं रही है। उनकी तरक्की की रफ़्तार को तेज बनाने के लिए अगर कुछ किया नहीं गया तो वैसी अवस्था में हमारे सामने नयी-नयी समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ खड़ी हो जायेगी। देश में जो कमजोर वर्ग और निचले तबके के लोग हैं उन्हें काम देने या मुहैया करवाने का सवाल इस सम्बन्ध में हमारे सामने एक खास ममला है। किसी देश में इससे बड़ कर बुरी बात कोई नहीं हो सकती कि उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो। ऐसी स्थिति खुद बेरोजगार व्यक्ति के लिए और देश के लिए भी उतनी ही बुरी है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति को भी जिन्दा रखना होता है। उसे खाने-पहनने के लिए भी चाहिए।

भारत : गरीबों का देश

देश को दो प्रकार का भार वहन करना पड़ता है। एक ऐसे व्यक्तियों का जो उपभोक्ता हैं पर उत्पादक नहीं और ऐसे लोगों का जो उत्पादक हैं लेकिन उपभोक्ता नहीं बन सकते। देश में ऐसे खुशहाल आदमी हैं, जो खुद उत्पादन नहीं करते बल्कि दूसरों के श्रम और कमाई पर जीते हैं, पलते हैं तथा ऐसे लोग भी हैं जिन्हें काम व कमाई करने का मौका नहीं मिलता। भारत गरीबों का देश है। शायद ससार के उन अन्य देशों के सम्बन्ध में भी यह बात सच है, जिन्होंने तरक्की की और धनवान

* गांधीग्राम (मडुराई) में 'राष्ट्रीय एकता' पर सम्पन्न विचार गोष्ठी में १ दिसम्बर १९६२ को दिष्टे गये समावर्तन भाषण से।

वने। किन्तु बाद में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के कारण पश्चिम के देश यह जान गये कि गरीबी कैसे दूर की जा सकती है। यह सही है कि आज भी पश्चिम के देशों में समस्याएँ हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने पर्याप्त उत्पादन कर लिया है। भारत तथा एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों जैसी गरीबी पश्चिम के देशों में नहीं है। गरीबी केवल अधिक उत्पादन से ही दूर की जा सकती है और अधिक उत्पादन आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक के तौर-तरीके अपना कर ही किया जा सकता है। हमारे योजना आयोग ने बुनियादी दृष्टि से सोचा और बड़े-बड़े बाँध, बिजली-घर आदि बनवाये। यदि हम गाँव में बिजली पहुँचा देते हैं, तो हम उस गाँव का कायकल्प करने लगते हैं।

आप गाँव में, उसकी खेती में, उसके लघु-स्तरीय उद्योगों में तथा उसकी सामान्य सुविधाओं में धीरे-धीरे करके क्रांति लाते हैं। योजना आयोग ने बड़े और बुनियादी उद्योगों को प्रोत्साहन देना शुरू किया। इसके बाद हमें यह सुनिश्चित करना था कि बुनियादी उद्योगों पर किसी एक उद्योगपति का स्वामित्व न हो कर राज्य की मिल्कियत हो अर्थात् वह सार्वजनिक विभाग में हो। हमें अपने लोकतन्त्रात्मक स्वरूप के अन्तर्गत रहते हुए उत्पादन और वितरण की समस्या पर विचार करना पड़ता है। मैं नहीं कह सकता कि कस्बों और गाँवों के लाखों-करोड़ों लोगों तक औद्योगीकरण की प्रक्रिया को पहुँचाने में कितना समय लगेगा।

नीचे से निर्माण

हमारे सामने एक दूसरा तरीका और है, जिसमें किसी तरह का संघर्ष नहीं है। वह तरीका है नीचे से शुरूआत करने का। यह एक ऐसा तरीका है जिस पर गांधीजी ने बहुत जोर दिया था। मौजूदा हालत में जिस चीज को उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा उस पर उन्होंने जोर दिया। मैं नहीं कह सकता और न ही मैं यह मानता

हूँ कि कोई दूसरा ऐसा कह सकता है कि मौजूदा हालत में गांधीजी क्या सलाह देते। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वे हमें निश्चय ही सलाह देते कि निचले तबके के लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना चाहिए। आज देश में जैसी हालत है, उसकी दृष्टि से यह निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल कर कोई अच्छे आसार सामने आये, इसका बिना कोई इन्तजार किये सही चीज करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यदि आप फिलहाल सही काम नहीं करते हैं तो आगे चल कर सभी प्रकार का तनाव और संघर्ष खड़ा होगा। इसलिए बुनियादी उद्योगों, बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाओं जैसी देश को आगे बढ़ानेवाली बुनियादी बातों पर जोर देने के साथ ही साथ हमें निचले तबके के लोगों—जिनमें अधिकांशतः किसान और ग्रामीण कारीगर आते हैं—को तुरन्त लाभ पहुँचानेवाली चीजों पर भी जोर देना होगा। हमें अपने उद्योगों, कृषि, पशु-पालन, वनों तथा अन्य अनेक ऐसी ही चीजों का विकास करना होगा।

प्रति व्यक्ति आय

हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। हमारी आबादी के निचले स्तर पर कुछ किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय पर तुरन्त उसका अच्छा असर पड़ता है। यदि हमारे यहाँ लोहे और इस्पात के सयंत्र तथा अन्य इसी प्रकार के बड़े उद्योग हैं तो बहुत अच्छी बात है और भविष्य की दृष्टि से वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी है कि वनसे प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती। खेती, पशु-पालन, ग्राम और लघु उद्योगों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने यानी उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ किया जाय तो उससे तुरन्त निचले तबके के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इससे विभिन्न वर्गों में एकता की स्थापना को बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए, हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा और वह भी काफी हद तक। निस्सन्देह पिछले पन्द्रह वर्षों में भारत ने अनेक

दिशाओं में पर्याप्त प्रगति की है, किन्तु मोठे रूप में यह कहा जा सकता है कि यह प्रगति निचले स्तर की अपेक्षा ऊपर के स्तर पर ज्यादा हुई है। यह जानने के लिए काफी समय से एक समिति नियुक्त की हुई है कि आय का वितरण किस प्रकार हुआ है। कुछ महीनों में ही इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने की अपेक्षा है। तथापि, एक विकासशील देश में इस बात से बचा नहीं जा सकता कि आर्थिक विकास के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों से ऊपरी स्तर के लोग फायदा उठाये। इस प्रकार के व्यक्ति हो सकता है अधिक कर्मठ या उत्साही हो और उनके पास साधन-स्रोत भी होते हैं। यह वैसी ही बात है कि एक कम साधन-सम्पन्न किसान की अपेक्षा एक अच्छे किसान की हालत बेहतर होती है।

सहकार: सर्वोत्तम मार्ग

हमें एक छोट किसान को, उसे अवसर प्रदान करते हुए, उसका दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए, और उसे अधिक साधन-स्रोत व तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाते हुए एक अच्छा किसान बनाने की समस्या का सामना करना है। भारत में खेतों का आकार आम तौर पर छोटा है, इसलिए कृषि सुधार बहुत-कुछ सहकारी तौर-तरीके अपनाने पर निर्भर है। मैं नहीं सोचता कि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग हो सकता है। वास्तव में कुछ अन्य चीजें भी ऐसी हैं, जिनसे किसान को सहायता मिल सकती है। लेकिन सहकारी तरीका बहुत जरूरी है। वैसी हालत में सहकारी संगठन से प्रत्येक किसान को अधिक साधन-स्रोत मिलते हैं और उसके लिए खेती को पशु-पालन तथा लघु स्तरीय उद्योगों के साथ जोड़ना आसान है। इस प्रकार कृषि विभाग में सर्वांगीण विकास कार्यक्रम बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सहकार के क्षेत्र

में कितनी प्रगति होती है। सहज रूप से ही खेती अन्य अनेक कामों से जुड़ी हुई है और उन्हें केवल सहकारी तरीके से ही सुसंगठित किया जा सकता है।

ग्रामीणों की स्थिति में सुधार

जापान में कोई पन्द्रह वर्ष पूर्व भूमि सुधार हुआ। मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर भूमि-सीमा सात एकड़ रखी गयी। भारत में भूमि-सुधार की दिशा में उठाये गये कदमों पर काफी आलोचना व छोटाकसी की गयी है। जापानी किसान ने भूमि सुधार के अन्तर्गत कम से कम भूमि रखते हुए भी उच्च जीवन-स्तर हासिल किया है, क्योंकि वह अच्छे और आधुनिक तौर-तरीकों से खेती करता है। परिवार के सभी सदस्य—बाप-बेटा, माँ-बेटी सभी—खेती में काम करते हैं। खेती के अलावा वह पशु-पालन, मुर्गी-पालन व लघु उद्योगों का काम भी करता है। बड़े उद्योगों को प्रायः छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाता है और छोटे-छोटे उद्योग घरों में चलाये जाते हैं तथा उनके उत्पादन किसी सामूहिक केन्द्र में ले जाये जाते हैं, जहाँ उन्हें जोड़ा जाता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम बहुत शिक्षा ले सकते हैं। हम अपने बड़े उद्योगों को कितना भी विकसित क्यों न करें, फिर भी बहुत-सी आबादी उनके कार्य-क्षेत्र से बाहर रहेगी, जिसे आवश्यक रूप से ही कृषि, लघु स्तरीय तथा ग्राम उद्योगों और स्थानीय साधन-स्रोतों पर निर्भर करना पड़ेगा। यही कारण है कि इस महान समस्या से लोहा लेने के लिए हमें अपनी कृषि तथा लघु स्तरीय व ग्राम उद्योगों और यहाँ तक कि कुटीर उद्योगों में भी सुधार लाना होगा। अतएव यद्यपि बड़े उद्योग महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनकी दृष्टि से ही सोचना पर्याप्त नहीं होगा। हमें गाँवों में रहनेवाली जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के सम्बन्ध में भी सोचना होगा।

अहिंसा के सामाजार्थिक निहितार्थ*

उछरंगराय न. ढवर

गाधीजी ने महसूस किया कि पाश्चात्य जीवन मार्ग का बिना सोचे-समझे यत्रवत अनुकरण करने से देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और न ही इस प्रकार की नकल करने से भारतीय जनता की प्रतिभा का विकास हो सकता है।

मह'पुरुषों के उपागम में सदैव ही कुछ ऐसी बात पायी जाती है, जिसका मूल्य स्थायी होता है। अब यह उनके जीवन का अध्ययन करनेवाले व्यक्ति पर है कि वह उस स्थायी मूल्यवाले हिस्से को पृथक कर ले, उसे छोट ले। वह इस सम्बन्ध में पर्याप्त नीर-क्षीर विवेकी होना चाहिए कि उन्होंने कई बातें ऐसी कही अथवा की जिनका अस्थायी महत्व था। उदाहरण के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम बनाये और नीतियाँ निर्धारित की वे केवल उस वक्त ही प्रभावशाली हो सकी, क्योंकि उन्होंने खास अवसरों की आवश्यकताएँ पूरी की। उन्हें सदैव के लिए उपयोगी समझना गलत होगा। यदि उन्हें किसी ऐसे वक्त काम में लाने का प्रयत्न किया जाय जब न तो वे किसी परिस्थिति के ही अनुकूल हों और न समय के तकाजे के ही, तो निश्चय ही असफल होगी।

गाधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जो कुछ किया वह उस वक्त अत्यधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन एक भारतीय तथा समूचे भारत के लिए जो वस्तु चिर-स्थायी महत्व की बनी रहेगी वह है सत्य और न्याय के अनिवार्यत आध्यात्मिक आधार पर मानवीय सम्बन्धों का निर्माण अथवा विकास करने के लिए अहिंसा का

विश्वस्त व शक्तिशाली माध्यम। इसी प्रकार हम आज की तरह सैनिक दृष्टि से अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं, लेकिन स्थायी महत्व की बात यह महसूस करना है कि युद्ध और हिंसा में बहुत ही खतरनाक बातें छिपी हुई होती हैं। उन्होंने ऐसे विवाद पैदा कर दिये हैं कि उन्हें केवल अहिंसात्मक उपागम से ही सुलझाया जा सकता है। इस स्थिति को आज विश्व के सभी महापुरुष महसूस करने लगे हैं। इसी तरह गाधीजी जो सामाजार्थिक स्वरूप निष्पादित करने की कोशिश कर रहे थे, वह स्थायी मूल्य की तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु है। यहाँ भी हमें इस सम्बन्ध में सतर्क रहना होगा कि हम उन बातों पर जोर न दें जो अस्थायी मूल्य की थीं अथवा जो उनकी आत्मनिष्ठ प्रतिक्रियाओं की उपज थीं। वैसा करने का अर्थ होगा कि उन्हें वर्तमान सन्दर्भ में हमने गलत समझा है। इसके साथ ही उनके सामाजार्थिक उत्पादन में अनेक ऐसी अच्छी बातें हैं जिनका हमारे लिए चिरतन मूल्य है। यह हमारे खुद के हित का तकाजा है कि हम उनकी उपेक्षा न करें।

भावी भारत का चित्र

भारत के भावी स्वरूप के सम्बन्ध में १९४५ में भारत

* प्रस्तुत लेख अन्नमलै विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित 'गांधी व्याख्यान माला' का तृतीय व्याख्यान है। व्याख्यान केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय की प्रोमोशन ऑफ गांधीयन फिलॉसफी-गांधी दर्शन का प्रसार-नामक योजना के अन्तर्गत दिये गये थे। यह तीसरा व्याख्यान इस पत्रिका में मन्त्रालय की स्वीकृति से प्रकाशित किया जा रहा है। तथापि,

शिक्षा मन्त्रालय इस सामग्री की सर्वेसही के लिए उत्तरदायी नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं कि व्याख्यान में व्यक्त विचार भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। इस पत्रिका में प्रस्तुत विचार सामग्री का पुन प्रकाशन भारत सरकार और अन्नमलै विश्वविद्यालय की स्वीकृति से किया जा रहा है।

की दो महान विभूतियों—गांधीजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू—के बीच एक दिलचस्प पत्र-व्यवहार हुआ था, जिसमें गांधीजी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था

“मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि भारत को, और उसके जरिये समस्त ससार को सच्ची आजादी हासिल करनी है तो आज या कल इस तथ्य को मानना ही पड़ेगा कि लोगो को शहरो में नहीं, गाँवों में, महलो में नहीं झोपड़ियों में रहना होगा। शहरो और महलो में लाखों-करोड़ों व्यक्ति कभी अमन-चैन से नहीं रह सकेंगे। वैसी अवस्था में उनके सामने असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह जायेगा।

“मेरा खयाल है कि सत्य तथा अहिंसा के बिना मान-वता का सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ न होगा। यह सत्य और अहिंसा हमें ग्राम्य जीवन की सादगी में ही मिल सकती है और यह सादगी चरखे व उसके सिद्धान्तों में ही देखी जा सकती है। आज दुनिया अगर गलत रास्ते पर चल रही है तो मुझे उससे कोई भय नहीं है। हो सकता है भारत भी उसी रास्ते पर जाय और शमा के ईर्द-गिर्द ही चक्कर काट कर जल जानेवाले परवाने की तरह भस्म हो जाय। लेकिन आखिरी दम तक भारत को और उसके जरिये सारे ससार को उस विनाश लीला से बचाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

“मैंने जो कुछ कहा है उसका सार यही है कि आदमी को अपनी वास्तविक आवश्यकताओं पर ही सतोष करते हुए आत्म-निर्भर बनाना चाहिए। अगर उसमें इतना सयम नहीं है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। बूँद-बूँद से सागर बनता है, वैसे ही अलग-अलग आदमियों से ससार का निर्माण होता है। यह सर्वविदित सत्य है।

“जब मैं आधुनिक विज्ञान की तारीफ करता हूँ तो देखता हूँ कि उसकी सही दृष्टि से जो पुराना है

उसे ‘नया जामा’ पहनाया जाय और ‘नया रूप’ दे कर ठीक किया जाय। यह बिल्कुल न सोचे कि जिस ग्राम्य जीवन की मैं कल्पना कर रहा हूँ वह आज के जैसा होगा। आखिर, हर आदमी के अपने स्वप्न होते हैं। मेरी कल्पना का जो आदर्श गाँव है वह जानवरों की तरह गदगी और अन्वकार में नहीं रहेगा। उसके नर-नारी स्वतन्त्र होंगे और ससार में किसी का भी मुकाबला करने का सामर्थ्य उनमें होगा। उस गाँव में प्लेग, हैजा और चेचक की बीमारियाँ नहीं होगी, न कोई बेकार होगा, न कोई विलासी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। ऐसे गाँव में रेलगाड़ी, डाक व तारघर और अन्य ऐसी चीजों के होने की कल्पना करना सम्भव है।”

यदि हम इस चित्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तो पायेंगे कि गांधीजी एक कृषि-औद्योगिक स्वरूप के लिए कार्य कर रहे थे। इस प्रकार के स्वरूप अथवा गठन का प्रारम्भ भारी उद्योगों से नहीं होगा, जीवन-स्तर को कोई बहुत ऊँचा उठाना उसका उद्देश्य नहीं होगा, वह प्रतिस्पर्धात्मक भी नहीं होगा। फिर भी, वह सत्य और अहिंसा यानी सर्वोदय के सिद्धान्तों पर संचालित एक सुदृढ़ तथा सन्तुष्ट समाज की सुनिश्चितता अवश्य प्रदान करेगा। उक्त पत्र-व्यवहार से मोटे तौर पर यह उपागम सामने आता है।

स्वभाविक रूप से ही इस चित्र में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अस्थायी रूप से उपयोगी हैं और कुछ ऐसी हैं, जिनका स्थायी तथा महान महत्व है। द्वितीय श्रेणी में तीन बातें आती हैं जो गांधीजी के विचारों को पढ़ने पर आसानी से ढूँढी जा सकती हैं (१) ग्राम-प्रधान अर्थ-व्यवस्था पर जोर, (२) सादगीपूर्ण जीवन पर जोर, और (३) सहकारी सामाजार्थिक संगठन पर जोर। इस पर जोर देने के पीछे स्पष्टतः यह उद्देश्य था कि देश-वासियों के लिए सत्य और अहिंसा पर आधारित जीवन,

व्यतीत करना संभव तथा सरल हो। यह उनके जीवन का मूल मंत्र था।

आधुनिक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए उमने जो कुछ पढ़ा है उस सबके प्रति दृढ़ समर्पण उपागम एक चुनौती होगा। आधुनिक अर्थशास्त्र यह बताता है कि द्रुत गति से औद्योगीकरण आर्थिक प्रगति की कुंजी है। गांधीजी इस मान्यता का विरोध करते लगते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र इस बात का मुझाव देता है कि उच्च जीवन-स्तर का मतलब है खुशहाल समाज। गांधीजी, ऐसा प्रतीत होता है, इस मत को भी नहीं मानते। आधुनिक अर्थशास्त्र प्रतिस्पर्धा और भौतिक उत्प्रेरणाओं को आर्थिक प्रगति की एक परमावश्यक शर्त मानता है। गांधीजी इसका भी विरोध करते हैं। तथापि, उन्होंने किसी भी समस्या पर कभी भी नकारात्मक दृष्टि में विचार नहीं किया। यद्यपि यदा-कदा उन्होंने आधुनिक उपागमों अथवा दृष्टिकोणों की खामियों के सम्बन्ध में कुछ कहा, तथापि बुनियादी तौर पर उनका उपागम भारतीय स्थिति की कटु वास्तविकताओं में ढला था।

ग्रामोन्मुखी गठन

यह स्मरण रखना चाहिए कि गांधीजी कोई कूप-मण्डूक नहीं थे। उन्होंने विस्तृत संसार देखा था। पाश्चात्य देशों द्वारा की गयी महान आर्थिक प्रगति, उसकी गति और पूर्ण रोजगारी, जन-शिक्षण तथा साफ-सफाई व स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उसके योगदान के सम्बन्ध में उन्होंने सुना था। वे एक संवेदनशील व्यक्ति थे— मानवीय दुःख-दर्दों के प्रति संवेदनशील, फिर चाहे वे दरिद्रता से पैदा हुए हों अथवा बीमारी या अज्ञान से। वे नहीं चाहते थे कि देशवासी एक दिन के लिए भी और दुःख-दर्द सहें। तब फिर क्या कारण था कि वे ग्रामोन्मुखी गठन अथवा अर्थशास्त्रियों की भाषा में एक कृषि-औद्योगिक गठन पर जोर देते थे? किस कारण से वे पाश्चात्य ढंग के औद्योगिक गठन या स्वरूप का विरोध करते थे? उनका तर्क मूलभूत और भारतीय

अवस्थाओं की नितान्त आवश्यकताओं पर आधारित था।

यह कहना कि वे सुधारवादी थे अथवा भारत को संसार से अलग रखना चाहते थे, उनके प्रति अन्याय होगा। मानो, इसी लालन का उत्तर देते हुए उन्होंने एक बार कहा था

“मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवारें हों तथा उसके दरवाजे-खिड़कियाँ बन्द कर दी जायें। मैं चाहता हूँ कि संसार की सभी सभ्यताओं का यथा सम्भव मुक्त प्रवाह मेरे यहाँ हो, पर मैं उसी प्रवाह में बह जाने से इनकार करता हूँ।”

वे इस बात के प्रति आतुर थे कि विकास की प्रक्रिया में कहीं हम भारतीय समाज की मौलिकता को नष्ट न कर दें।

इसी प्रकार यह कहना उनके प्रति अनुदारता अथवा छिद्रान्वेषण होगा कि वे विज्ञान और प्रविधि के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा था-

“यदि ग्रामोद्योग की अपनी विशेषता कायम रखी जाय यानी उस पर कोई आँच न आये तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है कि ग्रामीण ऐसे आधुनिक यंत्रों और सरजाम तक का उपयोग करें जो वे प्राप्त कर सकते हों। सिर्फ उनका इस्तेमाल दूसरों का शोषण करने के साधन के रूप में नहीं होना चाहिए।”

उनका विश्वास था कि उनकी कल्पना के गाँव एक ऐसा सुदृढ़ और टिकाऊ आधार प्रदान कर सकेंगे जिस पर समूचे भारत का भव्य, विशाल भवन खड़ा रह सके। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की मौजूदा बुनियाद को अनावश्यक रूप से हिलाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्हें आशा थी कि आधुनिक विज्ञान और प्राविधि की सहायता से गाँव को ‘नया जामा’ पहनाना तथा ‘नया रूप’ देना संभव हो सकेगा और द्वितीय यह कि शहरी अर्थ-व्यवस्था का गठन ही कुछ ऐसा है जिसके सम्बन्ध में उनके मन में शका थी। विशाल वाणिज्य और बड़ी पूँजी इसके

आधार-स्तम्भ होते हैं। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था न तो उत्पादन के मामले में तथा न स्पर्धा के क्षेत्र में ही उसकी कोई बराबरी कर सकती है, और न ही वह शहरी अर्थ-व्यवस्था के उस प्रभाव के सामने टिक सकती है, जो वह समाचार-पत्रों, प्रचार व राजनीतिज्ञों के जरिये सरकार पर डालती है।

गांधीजी ने यह भी महसूस किया कि अतीत में भारत के गाँव काम करने के लिए तैयार सभी व्यक्तियों को अभिक्रम और सृजन शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करते थे। विदेशी शासन ने अपने खुद के फायदे के लिए लोगों से वे जरिये छीन लिए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ ग्रामीण जनता के सामने फिर से अभिक्रम और सृजनशक्ति का विकास करने का एक अवसर आया है। उन्हें इस अवसर से वंचित करना न तो ठीक ही होगा तथा न न्यायसंगत ही, वैसी अवस्था में तो और भी नहीं जबकि भविष्य में उन्हें उसी पैमाने पर वैसा ही क्षेत्र प्रदान करना असम्भव हो जाय। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, विज्ञान और प्रविधि की सहायता से ग्रामोन्मुखी गठन को 'नया जामा' पहनाया जा सकता है तथा उसे 'नया रूप' दिया जा सकता है। राष्ट्र के सीमित साधन-स्रोतों को देखते हुए वह कम से कम कष्टप्रद साबित हो सकता है और प्रबन्ध, यातायात तथा पर्यवेक्षण पर होनेवाले खर्च से भी बचा जा सकता है।

सर्वांगीण उपागम

गांधीजी को इस बात का यकीन था कि आर्थिक आधार के रूप में कृषि, पशु-पालन और प्रशोधन उद्योगों को सहकारिता के सूत्र में बांध कर भावात्मक तथा सांस्कृतिक आधार के रूप में और बुनियादी तालीम कार्यक्रम के जरिये, जिसमें एक महान देश के निर्माण में लगे सभी व्यक्तियों के मूल्य और मान-मर्यादा पर जोर दिया जायेगा, बड़ी सरलतापूर्वक देश के जीवन में—सामाजिक वर्गों का उनके उद्गम स्थल पर ही एकीकरण कर—एक्य स्थापित किया जा सकता है। वे चाहते थे कि राज्य की सत्ता तथा विशाल पूँजी और व्यापार

की शक्ति मनुष्य के मानवीय पहलू के सहायक हो। उनके अनुसार किसान, पशु-पालक और कारीगर भारत के भाग्य विधाता हैं तथा सबसे पहले उन्हें शक्ति-शाली बनाया जाय। यह एक सर्वांगीण उपागम था। पचायत, सहकारी समितियाँ और बुनियादी तालीम सामाजिक परिवर्तन लाने के तीन मुख्य साधन थे।

शहरी अर्थ-व्यवस्था के दोष

इसके विपरीत, गांधीजी के अनुसार शहरी अर्थ-व्यवस्था एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बचे-खुचे उद्योगों को भी तहस-नहस कर देगी और ग्रामीण श्रम-शक्ति में जो पूर्ण तथा अल्प बेकारी है उसकी स्थिति को बदतर कर देगी। यह अर्थ-व्यवस्था एक ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहन देती है, जिसमें स्वार्थपरता और ऐशो-आराम की प्रधानता होती है। ग्राम्य संस्कृति का आधार श्रम होता है। शहरी अर्थ-व्यवस्था मौलिक मानवीय गुणों की विच्छिन्नता को प्रोत्साहन देती है। वह ग्रामीणों के सामने निष्क्रियता और जड़ता का एक ऐसा नमूना पेश करती है जो न तो जनता के ही हित में होगा और न देश के ही। शहरी जीवन-स्तर का एक पहलू यह भी है कि वह अधिकाधिक उपभोग की ओर निर्दिष्ट है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी लोगों के जीवन-स्तर में असमानता बढ़ती जायेगी तथा उस अन्तर की खाई को पाटना मुश्किल होगा। उससे आम जनता में फूट पैदा होगी।

भारत में अवस्थित उस वक्त की जिन विशेष अवस्थाओं से बाध्य हो कर गांधीजी जिस निष्कर्ष पर पहुँचे उस पर विचार करने से पूर्व यह जानना वाञ्छनीय होगा कि ऐसे कौन-से कारण थे जिनकी वजह से वे आधुनिक पाश्चात्य आर्थिक गठन या स्वरूप का आग्रहपूर्वक विरोध करते थे। आधुनिक आर्थिक उपागम के प्रति उनके विरोध को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। उनके अनुसार मानव पशु से इस माने में भिन्न है कि उसके हाथों में औजार है। मानव प्राणी के नाते उसकी प्रगति परिपूर्णत इस बात पर निर्भर

करती है कि उसे आने अभिक्रम और मृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करने का कितना अवसर मिलता है। उत्पादन के पार्श्वान्य तरीके आदमी को उक्त दोनों पहलुओं में वंचित कर देते हैं और वह एक यंत्रवत प्राणी बन जाता है। द्वितीय, उन्होंने महसूस किया कि औद्योगिक सम्यता का समूचा सबोध ही, इस पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के उद्देश्य के एक अप्राकृतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को उसके अस्तित्व का जो मुख्य उद्देश्य है उससे दूर ले जाता है। मनुष्य की कुछ प्रेरणाएँ पशु सदृश्य होती हैं, किन्तु जीवन के प्रति उसके दर्शन की वही अन्तिम मर्यादा नहीं है। प्रकृति ने उसकी रचना इसलिए की है कि वह अपने उच्च और आध्यात्मिक जीवन के लिए उसके (प्रकृति के) सपने को साकार करे। ज्ञान या चेतना का वरदान उसे इसलिए नहीं मिला है कि वह पालतू बिल्ली बन कर रह जाय। उसे प्रकृति ने स्वतंत्र बनने, जिम्मेदारियाँ सम्हालने, ज्ञान प्राप्त करने, सम्मान अर्जित करने तथा अपने साथियों की खोज-खबर लेने के लिए बनाया है, ताकि वह अपने आपको पहचाने। पार्श्वान्य दृष्टिकोण न केवल उसे गलत रास्ते पर ही ले जाता है, बल्कि उसके अस्तित्व के लक्ष्य को भी विकृत कर देता है और स्वतंत्रता, ज्ञान व सम्मान के अर्थ को ही भ्रष्ट कर देता है। गांधीजी का मुख्य उद्देश्य हमारी यात्रा का मार्ग निर्दिष्ट करना था, फिर चाहे लक्ष्य तक पहुँचने में हमें कितना भी समय क्यों न लगे, पर हम गुमराह न हों।

आधुनिक समाज के चरित्र-चित्रण और जिस दिशा में वह आगे बढ़ रहा है, उसके सम्बन्ध में पश्चिम में भी साहित्य की अभिवृद्धि हो रही है। एरिक फ्रोम उत्पादन के प्रति पार्श्वान्य उपागम की विवेकशीलता पर शका उठाते हैं। जॉर्ज ओरवेल (Orwell) ने अधिकांश मानवीय गुणों से वंचित, एक निरकुश सत्ता द्वारा संचालित समाज के आत्माविहीन स्वचलन का चित्र उपस्थित किया है। आल्डुस हक्सले ऐसे लोकतांत्रिक समाज की तस्वीर खींचते हैं जो आवश्यकता

में अधिक सगठन तथा रासायनिक प्रबोधन और कृत्रिम नीद के विमृग्यकारी प्रचार के कारण अपने मानवोचित गुणों की सुब-बुब खोता जा रहा है।

मनुष्यत्व से वंचित

उत्पादन तथा सामाजिक सगठन के पार्श्वान्य तौर-तरीकों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए सेन सोसायटी (विवेकी समाज) के महान लेखक श्री एरिक फ्रोम कहते हैं

“ओखले तथा अन्य दो लेखक (हक्सले और जमेतिन (Zamyatin) केवल यह सकेत करते हैं कि व्यवस्थापकीय औद्योगीकरण का नया स्वरूप—जिसमें आदमी यंत्र बनाता है, जो आदमी की तरह काम करते हैं और आदमी का इस रूप में विकास होता है कि वह यंत्रवत काम करता है—मनुष्यत्व से वंचित तथा पूर्ण विलगाव करनेवाले एक ऐसे युग का जनक है, जिसमें आदमी का वस्तु में रूपान्तरण हो जाता है और वह उत्पादन तथा उपभोग का पुर्जा मात्र बन कर रह जाता है। तीनों लेखक इस बात का सकेत करते हैं कि यह खतरा केवल रूसी अथवा चीनी प्रकार के साम्यवाद में ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खतरा है जो उत्पादन व सगठन के आधुनिक तौर-तरीकों में अन्तर्निहित है, और सापेक्षिक तौर पर वह विभिन्न विचारधाराओं से अलग है।”

हक्सले, फ्रोम के उक्त विचार का समर्थन करते हैं और उत्पादन तथा सगठन के इस पार्श्वान्य तरीके का व्यक्ति व समाज पर पड़नेवाले सभ्य प्रभाव का जिक्र करते हुए लिखते हैं

“पिछली शताब्दी के दौरान प्रविधि के क्षेत्र में क्रमिक प्रगति के साथ ही सगठन की दिशा में भी उन्नति हुई है। जटिल सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल ही जटिल यंत्रों का निर्माण करना पड़ा है, ताकि उत्पादन के नये साधन के रूप में वह सुगमता-पूर्वक काम कर सके। इन सगठनों के अनुरूप

व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विघटन करना पडा, उन्हें अपनी महज भिन्नता मिटानी पडी, अपने को स्तरीय पद्धति के मुताबिक ालना पडा, स्वयं-चालित बन जाने के लिए भरसक प्रयास करना पडा।

“कोई सगठन न तो चेतन है और न जीवित ही। उसका महत्व व्युत्पादक होने और साधन बनने में है। वह स्वयम् में ‘शिवम्’ नहीं है। वह उस हद तक ही ‘शिवम्’ है जिस हद तक वह समष्टि के अग स्वरूप व्यष्टि का कल्याण करता है। सगठन को व्यष्टि में अधिक प्राथमिकता देना साध्य को साधन के आधीन करना है। साध्य को साधन के आधीन करने से क्या परिणाम निकलता है, यह हिटलर और स्टालिन के कृत्यों से पूर्णत स्पष्ट हो चुका है। उनके नृशस शासन में हिंसा और प्रचार, सिलसिलेवार आतंक और बाकायदा मानसिक दिग्भ्रम के समिश्रण द्वारा साध्य सगठनात्मक साधनों के आधीन कर दिया गया था।”

उत्पादन तथा सामाजिक सगठन के तौर-तरीको अथवा स्वरूप और मानव के गुणात्मक विकास के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण करने के लिए काफी विस्तार में जाने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रविधि के क्रमिक विकास में हम देखते हैं कि समृद्ध समाजों में कुछ घटनाएँ घटित होती हैं इच्छाएँ अधिकाधिक रूप से बढ़ती जाती हैं, मानवीय सम्बन्ध अधिकाधिक व्यावसायिक बनते जाते हैं, ध्यानाकर्षण और पूर्ति के सम्बन्ध में प्राथमिकताएँ मानव के स्थान पर सामग्री को दी जाने लगती हैं, बाल दुराचार, मदिरापान, आत्म-हत्या, हत्या-प्रवृत्ति आदि जैसी सामाजिक बुराइयाँ बढ़ जाती हैं, और इन सबसे भयानक दुष्परिणाम तो यह निकलता है कि मानव किसी ‘घाट’ का नहीं रहता।

यह सच है कि भारत अभी ‘बटन दबाया और काम शुरू’ के युग से बहुत दूर है। फिर भी, यह स्वीकार

करना पड़ेगा कि शिक्षित भारत का हृदय पाश्चात्य समाज-व्यवस्था तथा पाश्चात्य उत्पादन पद्धति की ओर है। हम में से कुछ यदा-कदा बड़े-बड़े कारखानों, केन्द्रीकरण आदि के विरुद्ध तथा विकेन्द्रीकरण के पक्ष में बात करते हैं। लेकिन व्यक्ति के कथन का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो इस बात का है कि आर्थिक सगठनों का उद्देश्य क्या है, और इन संस्थाओं की व्यवस्था कोई दार्शनिक अथवा शिक्षाशास्त्री नहीं करते। वर्तमान समाज की बागडोर उन सगठनों के हाथ में है जो उद्योग और वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा, शेयर बाजार और सोने-चादी के व्यापार में लगे हैं और जिनका देश के समाचार-पत्रों व राजनीतिक सगठनों पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यही वजह है कि वे जो कुछ करते हैं, उसका महत्व है। स्पष्टतः लोगों के मन में ‘औद्योगिक समाज’ अथवा ‘प्राविधिक समाज’ का चित्र है। यही उनका निश्चित उद्देश्य है। यह उद्देश्य, जिसकी जड़ें नागरिक तथा सैनिक दोनों ही कामों के लिए तीव्र औद्योगीकरण में हैं, भारतीय समाज को भी उसी गतव्य पर ले जा सकता है, जिसके बारे में आज पाश्चात्य विचारक इतने परेशान हैं।

ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो इस बात में विश्वास करते हों कि इस प्राविधिक समाज को भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सकता है। सवाल यह है कि इसे कौन और कैसे ढालेगा? व्यक्ति चाहे कितने ही शक्तिशाली और बड़े क्यों न हों, आज जैसी अवस्था है उसमें वे मामूली भूमिका ही निभा सकते हैं। एक व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे केवल अपने सम्बन्ध में ही चयन करने की स्वतंत्रता है, कभी-कभी वह किसी छोटे या बड़े दल के लिए चयन कर सकता है, तथापि, जब एक व्यवस्था का सवाल आता है, जिसकी जड़ें मानवीय कमजोरियों पर आधारित हों और जिसके पीछे सत्ता, पैसे तथा बुद्धि का हाथ हो तब व्यक्ति को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। यह सच है कि आशंकित परिणामों के भय से हम विज्ञान और प्रविधि से होनेवाले लाभों को अस्वीकृत नहीं कर सकते, खास कर तब जबकि

हम जानते हैं कि घोर गरीबी, बीमारियाँ व अज्ञानता को देश में मिटा देने के लिए वे उपयोगी हो सकते हैं। अल्डुअम हक्सले ने पाश्चात्य सामाजिक गठन के उद्देश्यों सम्बन्धी यह प्रश्न उठाया और उन्होंने यह बात प्रकाश में लायी कि गांधीजी का क्या उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि “हमने सदैव अपनी अर्थ-व्यवस्था और प्रविधि को समाज के अनुकूल बनाने का चुनाव किया है, समाज को किसी परायी अर्थ-व्यवस्था और प्रविधि के अनुसार ढालने का नहीं।”

ऐरिक फ्रोम कुछ इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं “तथापि, प्रूथो, टालस्टाय और बाकुनिन, दुरखीन और मार्क्स, आईस्टन और स्विट्जर आदमी की और उसके साथ हमारी औद्योगिक व्यवस्था में क्या होता है, इसकी बात करते हैं। यद्यपि वे यह बात भिन्न-भिन्न रूपों में रखते हैं, तथापि इस सम्बन्ध में वे सभी एकमत हैं कि मानव ने अपना केन्द्रीय स्थल खो दिया है, आर्थिक उद्देश्यों के लिए उसे एक साधन बना दिया गया है, उसे अपने साथियों व प्रकृति से परकीय बना दिया गया है तथा उसने व्यक्ति-व्यक्ति तथा प्रकृति के बीच का ठोस सबंध खो दिया है, और यह कि अब उसका जीवन सार्थक नहीं रहा।

“उसका विवेक श्रेष्ठ है, उसका तर्क गिरता जा रहा है और वह सम्यता को तथा यहाँ तक कि मानवीय अस्तित्व को ही खतरे में डालता जा रहा है।”

हो सकता है गांधीजी ने वह सब नहीं पढ़ा हो जो पश्चिम में लिखा गया है। लेकिन उनकी अन्तर्दृष्टि ने यह जान लिया था कि पाश्चात्य ढंग अक्षम है, उसका मूल ही त्रुटिपूर्ण है और किसी भी अवस्था में वह भारतवासियों की प्रकृति तथा भारत की अवस्थाओं में उपयोग की दृष्टि से किसी भी हालत में अनुकूल नहीं है। जहाँ उनका दृष्टिकोण धार्मिक भाषा में व्यक्त हुआ वहाँ यह भी है कि उसमें व्यावहारिकता की कमी नहीं थी।

अतः हमें समस्या के उस व्यावहारिक पक्ष पर थोड़ा विचार करना चाहिए जिसमें प्रेरित होकर उन्होंने ग्रामोन्मुख गठन पर दिन-रात इतना अधिक जोर दिया।

व्यावहारिक तथ्य

गांधीजी के अनुसार भारत का भविष्य भारतीय जीवन के तीन बुनियादी पहलुओं द्वारा निश्चित होने-वाला है। वे तीन पहलू हैं

अ जनता का सामाजिक दृष्टिकोण,

आ राष्ट्रीय जीवन पद्धति अथवा देश के साधन-स्रोतों के अनुसार जीवन-स्तर, और

इ भारत की आबादी की विगलता को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक गठन का स्वरूप।

हम उनके सामाजिक उद्देश्यों के तात्त्विक पहलू पर विचार कर चुके हैं। उनका विश्वास था कि मानव जीवन का परमावश्यक उद्देश्य भौतिक साधनों की सम्प्राप्ति नहीं बल्कि आत्म शुद्धि के जरिये ईश्वर की खोज है, जिसे उन्होंने सत्य की खोज कहा था। उनका यह आग्रह था कि इसी जीवन दर्शन के लिए भारत जीवित रहा है और काम कर रहा है।

राष्ट्रीय जीवन पद्धति के सम्बन्ध में गांधीजी ने जोर दे कर कहा

“सम्यता वास्तव में मागे बढ़ाते जाने में नहीं बल्कि जान-बूझ कर और स्वेच्छापूर्वक उन्हें सीमित रखने में निहित है। इसी से वास्तविक हर्ष और सतोष प्राप्त होता है तथा सेवा करने की शक्ति बढ़ती है।”

व्यक्तिगत खुशहाली के इस पक्ष के अलावा, जिस पर लोगो के अलग-अलग मत हो सकते हैं, गांधीजी भारतीय स्थिति की वास्तविकताओं के प्रति परिपूर्ण रूप से सजग थे। जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, जो प्रश्न उन्होंने देश के सामने रखा वह यह था कि उपलब्ध वित्तीय साधन-स्रोतों को ध्यान में रखते हुए क्या देशवासी अपनी वास्तविक आवश्यकताओं से

ऊँचा जीवन-स्तर बनाये रखना बर्दाश्त कर सकते हैं ? यह सवाल आज भी हमारे सामने है। सांख्यिकीय आकड़ों से पता चलता है कि १९६१-६२ में देश की आबादी के नितल दस प्रति शत लोगों की प्रति व्यक्ति मासिक आय ६६० रुपये थी, और उनसे ऊपर की पाँच श्रेणियों में आनेवाले व्यक्तियों की क्रमशः ९६० रुपये, ११७० रुपये, १३२५ रुपये, १७३५ रुपये, और २१५० रुपये। इस प्रकार इन अकों के अन्तर्गत भारत की ६० प्रति शत जन-संख्या आ जाती है।

औद्योगिक स्वरूप

इसके समक्ष पोषण सलाहकार समिति का अनुमान है कि एक व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य भलीभाँति बनाये रखने के लिए ३५ रुपये मासिक तो अकेले भोजन के लिए ही चाहिए। यह उपलब्ध नहीं है तो इसमें सरकार या अन्य किसी की गलती नहीं है। लेकिन मैं जो वस्तु स्थिति है, वह बता रहा हूँ। भारत अगर आन्तरिक सघर्ष से बचना चाहता है तो उसे यह बुनियादी तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकांश जनता का जीवन-स्तर इस शताब्दी के अन्त तक गुजर-बसर करने की अवस्था से शायद ही ऊपर उठे। गांधीजी का विचार था कि इन परिस्थितियों की दृष्टि से न्यूनतम और अधिकतम उपभोग स्तर के बीच का अन्तर ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्यावहारिक और नैतिक विचार की दृष्टि से यह सुझाव मिलता है कि राष्ट्रीय जीवन पद्धति कुछ ऐसी होनी चाहिए, जो देश के बूते से बाहर की चीज न हो। वर्तमान शताब्दी के अन्त में नितल श्रेणी के २० प्रति शत लोगों की प्रति व्यक्ति मासिक आय बढ़ कर २० रुपये हो जाने की सम्भावना है। उच्च जीवन-स्तर वाले वर्गों को बढ़ावा देना और खास तौर पर अपरिमाजित प्रदर्शन की ओर प्रवृत्त होना सकटमय होगा, जबकि अधिकांश जनता महज दो जून रोटी भर प्राप्त कर सकने की स्थिति में ही है।

लेकिन गांधीजी के लिए जीवन पद्धति से भी अधिक

महत्वपूर्ण सवाल था औद्योगिक स्वरूप का। देश में मौजूद पूर्ण और अर्ध बेकारी की स्थिति का उन पर बहुत असर पड़ा था। यहाँ तक कि भारत में आज भी एक करोड़ व्यक्ति पूर्ण और इससे भी दुगुने लोग आंशिक रूप में बेरोजगार हैं। प्रति वर्ष देश की श्रम-शक्ति में २५-३० लाख व्यक्ति नये आ जाते हैं। ग्रामीण आबादी में पन्द्रह प्रति शत लोग भूमिहीन श्रमिक हैं। जितने लोगों के पास जमीन है उनमें से पन्द्रह प्रति शत के पास एक-एक एकड़ से भी कम है। गांधीजी ने महसूस किया कि उत्पादन के पाश्चात्य तौर-तरीकों में जो अन्तर्निहित कमजोरियाँ हैं वे तो हैं ही लेकिन भारत में औद्योगीकरण की समस्या पर विचार करते वक्त भारत के पास जो बहुत ही कम साधन-स्रोत हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए।

अर्थ-व्यवस्था के अभिन्न अंग

पूर्ण और अर्द्ध बेरोजगारी की जो विशाल संख्या है, वह यद्यपि ग्रामीण आबादी का एक अभिन्न अंग है तथापि वे फिलहाल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की परिधि में नहीं आते। उनका गहरी गठन में भी कोई स्थान नहीं है। गांधीजी का विचार था कि उन्हें इस प्रकार लगाया जाय कि वे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अभिन्न अंग बन जायें। इतनी बड़ी और वृद्धिशील संख्या में लोगों को बिना काम के छोड़ना उनकी दृष्टि में खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि जब तक इतने अधिक लोगों के लिए स्थायित्व सुनिश्चित न कर दिया जाय तब तक भारत मजबूती या स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकता। इसी कारण उन्होंने कृषि-औद्योगिक गठन का सुझाव दिया और उद्योग के क्षेत्र में केन्द्रीकरण का विरोध किया। जिन अर्थशास्त्रियों ने रोजगारी की समस्या का अध्ययन किया है, उनके लिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि गांधीजी ग्रामोद्योगों पर जो बल देते थे उसके लिए वे बिल्कुल ही गलत नहीं थे। आज की धारा उसी दिशा में उन्मुख हो रही है जिस दिशा का उन्होंने सकेत दिया था। अधिकाधिक रूप से यह महसूस किया जा रहा है

कि प्रशोधन उद्योग यथा सभव विकेन्द्रित ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जाय। लेकिन इसी से समस्या का पूर्ण समाधान हो जानेवाला नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय आर्थिक गठन में हमारी आबादी का यह विभाग स्थायित्व महसूस करे तो हमें और भी आगे बढ़ना होगा यानी कुछ और भी करना पड़ेगा तथा यह देखना होगा कि उनके जीवन को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है।

ग्रामीण आधार को शक्तिशाली बनाना

इसे प्रतिगामी कदम अथवा यह समझना गलत होगा कि ऐसा करना आदिकालीन अर्थ-व्यवस्था के लिए कोशिश करना है। जिस प्रकार हमारी प्राचीन अर्थ-व्यवस्था के प्रति हमारे मन में जो प्रेम है उसके कारण हम 'परिवर्तन के प्रति' आँखें नहीं बन्द कर लेनी चाहिए, उसी प्रकार 'परिवर्तन के प्रति' हमारे प्रेम के कारण हमें देश की वास्तविकताओं की ओर से भी आँखें नहीं मूंद लेनी चाहिए और फिर यह सोचना कि उद्योगों का केन्द्रीकरण करना ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें जनता की भलाई के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है, यह तर्क देना है कि वास्तविकताएँ जो भी हो विज्ञान व प्रविधि अपनाती ही चाहिए। अन्ततोगत्वा विज्ञान और प्रविधि मानव के लिए हैं मानव उनके लिए नहीं। केन्द्रीकरण अपेक्षाकृत कम आबादी-वाले देशों तक में बेकारी की समस्याएँ खड़ी कर रहा है। तब फिर भारत में तो पूर्ण रोजगारी मिल ही नहीं सकती, जोकि सघन रूप से बसा हुआ देश है। द्वितीय, विकेन्द्रीकरण का मतलब भारी और बुनियादी सामग्री तैयार करने वाले उद्योगों का अभाव नहीं है। जिसे भी इस सम्बन्ध में कोई शका अथवा भय है, वह १९३१ में स्वीकृत कांग्रेस के कराची प्रस्ताव का अध्ययन कर सकता है। किसी भी चीज को बिल्कुल त्यागने का विचार कभी भी नहीं रहा। विचार है देश की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की नींव मजबूत करने का। इस सम्बन्ध में जो भी चीज बाधक हो वह गांधीजी को स्वीकार नहीं थी। उनके लिए

ऐसी कोई भी चीज प्रतिबन्धित नहीं थी, जिससे उक्त प्रक्रिया में सहयोग मिले।

इस परीक्षण के आधार पर भारत को हर हालत में अर्थ-व्यवस्था के विकेन्द्रित गठन अथवा स्वरूप को शक्तिशाली बनाने के लिए भारी उद्योगों की आवश्यकता होगी। भारत को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिए आर्थिक निर्माण खर्च (जैसे मशीनें, बिजली, यातायात आदि) प्रदान करने के लिए भी भारी उद्योगों की आवश्यकता होगी। उसे बैंको, बीमा तथा वाणिज्य व व्यवसाय सम्बन्धी अन्य संस्थाओं की भी आवश्यकता होगी। तथापि उन सबके पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में एक ही विचार होगा कि ग्रामीण आधार को शक्तिशाली बनाया जाय।

भारतीय आयोजन

यह पूछा जा सकता है कि क्या भारतीय आयोजन इस आधार पर आगे बढ़ रहा है? इसका उत्तर देना सहल नहीं है। दो विचारधाराएँ हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि चन्द व्यक्ति क्या कहते हैं, इसका महत्व नहीं है। इसमें कोई सदेह नहीं कि जिस क्षेत्र का पलड़ा भारी है, वह इस उपागम के विरुद्ध है। भारत पिछले कुछ सप्ताह में अपनी नयी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत बन गया है। चीनी आक्रमण से उसकी रक्षा करना एक महान और अच्छा कार्य है। भारत को अपनी जन-शक्ति और प्राकृतिक साधन-स्रोतों का इस ढंग से विकास करने में मदद देने के सम्बन्ध में भी कि वह अपने परमावश्यक व्यक्तित्व का विकास कर सके, यही बात कही जा सकती है। कोई भी यह नहीं चाह सकता कि भारत किसी विदेशी अर्थ-व्यवस्था की नकल करे। भारत बाहर की जो चीज उसके 'हित' में हैं—उसे अपना सकता है लेकिन अन्ततोगत्वा अपनी समस्याएँ उसे स्वयम् को ही हल करनी पड़ेगी। कोई दूसरा उन्हें उसके लिए हल नहीं कर सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत ऐसा करने में सफल होगा।

हम ने चन्द उन बुनियादी तथा मूलभूत सत्य बातों

पर विचार किया है जो गांधीजी के उपदेशों से सामने आती है और जो देश के हित में स्थायी महत्व की है। उन्होंने हमें एक नया माध्यम दिया। उसी माध्यम से जाति अथवा धर्म, राष्ट्रीयता अथवा पद का बिना कोई भेद-भाव रखे और इस सम्बन्ध में कि दूसरा व्यक्ति हमारा मित्र है अथवा विरोधी, बिना किसी विभेद के व्यक्ति-व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध नियंत्रित होने चाहिए। उन्होंने हमें एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक प्रदान की है, जिससे हम असत्य और अन्याय से लोहा ले सकते हैं, फिर चाहे उनका उद्गम कुछ भी क्यों न हो। मानव की सबसे बड़ी समस्या—मानवीय अस्तित्व की समस्या—के सम्बन्ध में भी उन्होंने मानवता को आशा प्रदान की। अन्त में, उन्होंने हमें सामाजार्थिक क्षेत्र में अपनी प्रगति

मापने के लिए एक माप दण्ड भी दिया। आदमी का मार्ग सही होना चाहिए। उसे अपने इर्द-गिर्द के अन्य व्यक्तियों के बारे में भी सोचना चाहिए। समाज रचना का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जा सकता है कि समाज के सदस्य उसके सबसे कमजोर और अल्प विकसित व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। गांधीजी के अनुसार भारत के लिए सबसे सुरक्षित मार्ग यह है कि वह गाँव से प्रारम्भ करके आगे बढ़े। यह सच है कि हम एक ही छलाग में गांधीजी चाहते थे उतनी दूर नहीं जा सकते। तथापि, इस उक्त तथ्य रूपी दर्पण को सामने रखना हमारे लिए लाभप्रद होगा ताकि हम जान सकें कि हमारे पास क्या है, बल्कि इससे भी अधिक यह कि हम यह जान सकें कि हममें किस बात की कमी है। ●

पिताजी का परिवार में बड़ा सम्मान था और लोग उन्हें 'महर्षि' कहते थे, किन्तु मैं विरागी बना रहा तथा कुछ भी बाह्य शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद उन्हीं पाठ्य पुस्तकों की पुनरावृत्ति कष्ट साध्य प्रतीत होने लगी। 'महर्षि' स्वयम् मुझे पढ़ाने लगे, लेकिन उस क्रम को अब और जारी रखना मेरे बूते के बाहर था। अपने लोग समझने लगे कि मैं नान्तिक हो गया।

और फिर, शांतिपूर्वक अपने अनुभवों के प्रकाश से उनके आन्तरिक अर्थ का कुछ-कुछ मेरी समझ में आने लगा। मैंने यह भी समझा कि उन श्लोकों या मन्त्रों की मेरी अपनी व्याख्या हमारे शिक्षक की व्याख्या से मिलती नहीं थी। मैं अब भी ऐसा ही समझता हूँ कि मेरी व्याख्या में उन श्लोकों अथवा मन्त्रों में अन्तर्निहित सत्य के तत्त्व मौजूद थे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बच्चों को धर्म-शिक्षा देने में मैं क्यों विश्वास नहीं करता।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

खादी और अर्थ-व्यवस्था

वैकुण्ठ ल. मेहता

खादी उद्योग के लिए राज्य सहायता का नया स्वरूप अपनाता उत्पादन क्षेत्रों में ही उसकी विक्री बढ़ाने तथा कार्यक्रम के प्रति ग्रामीण समुदाय में और अधिक उत्साह पैदा करने के लिए कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई अभिरूपा का परिणाम है।

बम्बई के एक समाचार पत्र ने 'नया मोड' शीर्षक में अपने एक लेख में पूछा "खादी की विक्री पर मौजूदा छूट की जगह खादी वस्त्र की बुनाई पर उपदान" विषय को लिया है। इस लेख का अवश्य महत्व होता अगर लेखक महोदय ने 'नया मोड' शब्द के प्रति समझदारी दिखायी होती। जैसा कि पिछले चार वर्षों में खादी आन्दोलन में सम्बन्धित कार्यकर्तागण इस शब्द का प्रयोग में ला रहे हैं, यह शब्द खादी-उत्पादन को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अन्य पहलुओं के साथ जोड़ने और उसे ग्रामीण विकास की समग्र योजना का एक सजीव अंग बनाने के प्रयत्न का द्योतक है। 'नया मोड' में निहित एक दूसरी बात यह भी है कि उस विकास कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाने के लिए यह परमावश्यक है कि ग्रामीण समुदाय उसमें सक्रिय भाग ले। यदि इस विचार में निहित बातों को समझ लिया जाता है तो राज्य सहायता के एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप को अपनाने के महत्व को उपयुक्त रूप से महसूस किया जा सकता है।

समितियों के मत

खादी-उत्पादन पर उपदान की बात प्रारम्भिक तौर पर १९५३ में स्वीकृत की गयी थी—अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के गठन से भी पहले। उस स्वीकृतिका आधार यह था कि खादी उपयुक्त किस्म के उत्पादन कार्यों में ग्रामीण क्षेत्र के पूर्ण अथवा अल्प बेरोजगारों को बड़ी तादाद में रोजगारी प्रदान करती है—और अधिकाधिक रोजगारी प्रदान कर सकने की शक्यता

भी उसमें है। कि समूचे देहाती क्षेत्रों में शुरू करने के लिए हाथ-कताई सर्वाधिक उपयुक्त धरा है, ये मालूमान हैं १९३७ में बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त एक जाच समिति के जिसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय सर पुरुषोत्तम-दाम ठाकुरदाम और सदस्य-सचिव थे वर्तमान योजना आयोग के सदस्य डाक्टर विजयेन्द्र कस्तूरी रंग वरदराज राव। उसके १८ वर्ष बाद ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग समिति ने, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दत्तात्रेय गोपाल कर्वे (अब रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के डिप्टी-गवर्नर) और प्रोफेसर धनजय राव गाडगिल सदस्य थे, एक ऐसी योजना का अनुमोदन किया, जिसमें खादी-उत्पादन पर उपदान देने की बात आती थी। इसी बीच एक ओर उल्लेखनीय बात हुई। सर पुरुषोत्तमदास तथा उनके कई अन्य साथियों (जिनमें स्वर्गीय डा. जान मथाई भी थे) द्वारा प्रस्तुत १९४४ की बम्बई (उद्योग-पतियों की) योजना आयी, जिसमें मुनियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए कुटीर उद्योग के विकास का आग्रह किया गया था। द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनाते वक्त डा. पी. सी. महलनवीस तथा अर्थशास्त्रियों के एक दल ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किये थे।

बेरोजगारी की भारी समस्या

प्रायः इस प्रकार के तर्क उपस्थित किये जाते हैं कि हो सकता है खादी कार्यक्रम पर प्रारम्भिक रूप में विगुहृत 'संक्रमण राहत योजना' के बतौर ध्यान

दिया गया हो। समझ में नहीं आता कि 'सक्रमण' शब्द का उपयोग कर, क्या कहने की चेष्टा की जाती है। अगर उनका तात्पर्य यह है कि अर्थ-व्यवस्था की सक्रमण अवस्था में इस योजना को प्रश्रय मिला तो उन्हें यह भी जानना चाहिए कि सक्रमण काल आया भी है या नहीं। बारह वर्ष के आयोजन के बाद भी हम देखते हैं कि हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था गतिहीनता की अवस्था में पड़ी हुई है। कृषिक मजदूरों की कमाई, कुछ कम ही हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तत्वावधान में किय गये अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आबादी का कम से कम आधा हिस्सा अपने को जीवित भर रखने के लिए रोजाना ५० नये पैसे से भी कम खर्च कर पाता है और करोड़ों के पास औसतन महज आधे दिन का ही काम है।

बिक्री पर छूट

सरकारी आकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में फैली विस्तृत बेरोजगारी की बात तो अलग रही, यह अवस्था तो गाँवों में फैली अर्द्ध बेरोजगारी का ही परिणाम है। फिर शहरों और नगरों की ओर उनका ताता लगा हुआ है, जिससे वहाँ भी बेकारों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ भी सुनियोजित आर्थिक विकास के प्रभावों के बावजूद, बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर पहुँच गयी है। हमारे सार्वजनिक और निजी विभागों के विशाल उद्योग, छोटे या बड़े, जो उपभोक्ता और उत्पादक वस्तुओं के निर्माण में लगे हैं, इन १२ वर्षों के आयोजन काल में—जैसा कि हमारे योजना-अधिकारीगण भी भलीभाँति जानते हैं—जितने लोगों को रोजगारी दी जानी थी, उनसे बहुत ही कम लोगों को काम में लगा सके हैं।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। महज इसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए योजना अधिकारियों ने आम माँग की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करनेवाले ग्राम्य तथा लघु उद्योगों को योजना के अभिन्न अंग के रूप में विकसित करना स्वीकृत किया है। आयोजन के

विद्यार्थी जानते हैं कि योजना आयोग ने प्रथम पंच वर्षीय योजना में उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करनेवाले कुटीर तथा बड़े उद्योगों के लिए एक संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम का आधार निर्मित किया था। उस कार्यक्रम के एक सारभूत अंश के रूप में, इस बात का सुझाव दिया गया था कि यत्र और हाथ से उत्पादित वस्तुओं के लागत खर्च के फर्क को पाटने के लिए कुटीर उद्योगों के उत्पादनो के मूल्य पर छूट (रिबेट) दी जा सकती है। यही से हाथ करघा वस्त्र तथा खादी की बिक्री पर छूट का जन्म हुआ।

गुरु में यह सहायता १९५२ में मिलो में उत्पादित वस्त्रों पर लगाये गये उप-कर (सेस) से सम्बद्ध थी, किन्तु बाद में कपड़े पर उत्पादन-शुल्क का स्तर बढ़ जाने के कारण यह सहायता आम राजस्व से दी जाने लगी। इसकी कुल मात्रा का निर्धारण हाथ करघा वस्त्र अथवा खादी की बढ़ती या घटती माँग के आधार पर किया जाता है। चूँकि साल-दर-साल खादी की बिक्री बढ़ती गयी, इसलिए उसी के अनुसार छूट देने की माँग भी बढ़ी। किन्तु प्रति वर्ष बिक्री की इस वृद्धि के बावजूद, इधर हाल के वर्षों में उत्पादन उससे आगे बढ़ गया है। यह उत्पादन की वृद्धि इसलिए नहीं हुई कि उसमें किसी का स्वार्थ निहित है, बल्कि देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी इतने हृद दर्ज की है और कम आय मिलने के बावजूद चरखे पर काम करने की माँग इतनी ज्यादा व जोरदार है कि किन्ही-किन्ही स्थानों पर तो अपने परिवारों के लिए कुछ अर्जित कर सकने के लिए उत्सुक सूतकारों द्वारा लाये गये सूत की विशाल मात्रा को सम्भालना भी एक समस्या हो गयी है।

नयी योजना से लाभ

इस प्रकार हाथ कताई ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की एक निहायत जरूरत पूरी करती है। और चूँकि यह आवश्यकता बनी हुई है, इसलिए उत्पादन बढ़ सकता है, पर पिछले कुछ दिनों से आन्दोलन के कर्णधार, जिनमें कई

वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्हें महात्मा गांधी के नीचे यह काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, राज्य सहायता के मौजूदा स्वरूप की सीमाओं को महसूस करने लगे हैं। खादी के मूल्यान्तर को जहां राज्य द्वारा दी गयी छूट से आशिक तौर पर पूरा किया जाता है, वहाँ उसका अधिकांश उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ऐसी भावनाएँ जागृत हुईं कि उत्पादन के क्षेत्र में ही बिक्री को विकसित करने और ग्रामीण आबादी के अन्दर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में स्थानीय तौर पर उत्पादित हाथ-कते और हाथ-बुने वस्त्रों की देने के प्रति चेतना जागृत करने के प्रयास किये जाय।

राज्य सहायता देने के स्थान में अगर ऐसा परिवर्तन हुआ है कि उपभोक्ताओं के बदले स्थानीय उत्पादकों को सहायता दी जाय, तो उम्मीद यह की जाती है कि इससे ग्रामीण समाज में कार्यक्रम के प्रति अधिक उत्साह पैदा होगा। सूत कटाई और बुनाई, दोनों को उत्तरोत्तर रूप से ऐसा उत्पादक कार्य समझा जायेगा, जिससे कुछ कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष सहायता मिलेगी तथा एक परमावश्यक उपभोग की आवश्यकता की पूर्ति स्थानीय उत्पादन से हो जायेगी। बुनाई लागत के बराबर उपदान देने की नयी योजना—जिसमें ऊपरी खर्च नहीं पड़ेगा और उत्पादन स्तर पर ही उपदान दिया जायेगा—का लाभ यह होगा कि उत्पादन के क्षेत्र में वस्त्र का मूल्य सूतकारों के लिए नाम मात्र तथा गैर सूतकारों के लिए भी बहुत कम होने की वजह से आकर्षक होगा।

ग्रामीणों में अभिरुचि जगाना

इस तरह स्वावलम्बन को बढ़ावा देने में सकीर्ण मनोवृत्ति की कोई बात नहीं है। दर असल, इससे एक विशिष्ट सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है और इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस से आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर सृजनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है।

लार्ड बेवरीज ने अपनी रचना 'पिलर्स ऑफ़ सेक्यूरिटी' में 'आलस्य' को शैतान की सज्ञा देते हुए दरिद्रता के खिलाफ युद्ध में उसे परास्त करने की सलाह दी है। जबरदस्ती यानी इच्छा के विरुद्ध आलसी रहने की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, किन्तु इस स्थिति को जहाँ-कहीं भी लाभकारी काम की व्यवस्था के जरिये दूर किया जा सकता है, जैसे गाँवों में, वहाँ वैसे काम की व्यवस्था को आशिक तौर पर सरकारी खर्च पर प्रोत्साहन देना पड़ता है। उत्पादन की अवस्था में सहायता देने से उम्मीद है कि उत्पादन के संगठन के प्रति ग्रामीण समाज में दिलचस्पी पैदा होगी।

श्रम विस्थापन रोकना

फिलहाल खादी के अधिकांश उत्पादन की जिम्मेवारी सामाजिक कार्यकर्ताओं पर है, जो खादी आन्दोलन में उन दिनों से लगे हैं, जब महात्मा गांधी की प्रेरणा से इसका संचालन होता था। उन्हीं लोगों ने महसूस किया कि अब ऐसा वक्त आ गया है, जब इस कार्य की मूल धारा सूत-उत्पादन केन्द्रों में प्रवाहित हो और उन्होंने बिक्री से अधिक उत्पादन पर जोर देने की स्थिति का स्वागत किया है। अब से वे अपनी सेवाएँ खुले दिल से ग्रामीण समाज की मर्जी पर अर्पित करेंगे और उन्हें खादी कार्यक्रम को ग्रामीण सामाजिक विकास योजना के अभिन्न अंग के रूप में संचालित करने की जिम्मेवारी खुद उठाने में मार्गदर्शन देंगे।

यह बात निसर्कोच कही जा सकती है कि जो लोग हाथ कटाई और हाथ बुनाई को भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कुटीर उद्योग होने के तर्क उपस्थित करते हैं, उन्होंने अन्य ग्रामीण उद्योगों की उपयोगिता को कभी हेय नहीं कहा है। हमारी अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र की हाल की गतिविधियों को समझनेवाले यह जानते हैं कि खास तौर से विभिन्न किस्मों के ग्रामीण उद्योगों की उन्नति को योजना आयोग के तत्वावधान में एक सुगठित आधार प्रदान करने के लिए ग्रामीण उद्योग

आयोजन समिति का गठन करने की बात १९६२ के गुरु मे श्री जयप्रकाश नारायण की ओर से आयी थी, जो पिछले कई वर्षों से खादी आन्दोलन के महान समर्थको मे है। अगर कुछ उद्योगो मे नयी तकनीके अपनाने की कोशिश नही की गयी है—जैसा कि हाथ करघे की जगह शक्ति करघे का प्रयोग आदि—तो इसके पीछे महज एक ही सहज इच्छा है कि दीर्घ स्तर पर श्रम-विस्थापन को रोका जाय और इस प्रकार उन लोगो की सख्या बढाने की स्थिति से बचा जाय, जिनके लिए काम का बन्दोबस्त करना है।

गाधीजी मात्र खादी को ही शत प्रति शत स्वदेशी वस्त्र महज एक इस भाव से समझते थे कि जो हमारे

सर्वाधिक निकट है, उनकी सेवा की जाय। आज की परिस्थितियो मे सर्वोत्तम सेवा यही है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि पारम्परिक उद्योगो मे लगे लोग उखड कर कही अपने भाग्य के भरोसे भटकने न लगे। इस स्वदेशी भावना से हमारे अन्दर उन पारम्परिक उद्योगो की वस्तुओ को सरक्षण प्रदान करने की महज प्रेरणा ही उत्पन्न नही होनी चाहिए, बल्कि राज्य तथा राज्य के निर्देश मे समाज के कुछ सर्वाधिक कमजोर वर्गों के उत्पादन और सृजनात्मक प्रयासो को जीवित रखने तथा मजबूत बनाने के प्रयासो के प्रति साराहना व समर्थन के भाव भी उत्पन्न होने चाहिए।

बम्बई. २९ दिसम्बर १९६३

शिक्षा ने अभी तक प्रविधि को मानवीय माध्यम के रूप मे स्वीकार नहीं किया है। यह विचार कि अगर इतिहासकार नही बनना है तो इतिहास पढ़ने मे कोई तुक नही है, हेय समझा जायेगा—और ऐसा समझना सही भी है। किन्तु यह समझना कि अगर आपको प्राविधिज्ञ नही बनना है तो प्रविधि सीखने से क्या लाभ, पूर्णत स्वाभाविक प्रतीत होता है। पर वस्तुतः ऐसा खयाल भी हेय है ; क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि प्रविधि के सिद्धान्त अर्थात् काम करने के सुव्यवस्थित ज्ञान को उपयोग मे लाने की कला और विज्ञान के बारे मे कुछ जानता नही है तो वह अपने आपको पर्याप्त रूप से शिक्षित कहने का अधिकारी नही है।

—सर एरिक अँशबी. 'इन्वेस्टमेण्ट इन
मैन', न्यू साइन्टिस्ट, लन्दन।

हाथ कागज उद्योग में निस्यन्दक पत्र का उत्पादन

सदाशिव राव और बालचन्द्र मा. अग्शीकर

वैज्ञानिक और औद्योगिक कार्यों के लिए निस्यन्दक पत्र की बड़ी मांग है। इंग्लैण्ड और जर्मनी में इसका उत्पादन हस्त प्रक्रिया से होता है। हमारे देश में जितने भी निस्यन्दक पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है अभी तक वे आयात किये जाते रहे हैं और अब आयात पर रोक लगाने से उनका मिलना दुर्लभ हो गया है। निस्यन्दक पत्र के निर्माण में विशिष्टता प्राप्त करनेवाले हाथ कागज केन्द्र यह कमी पूरी कर सकते हैं।

हाथ कागज उद्योग में ऊँची जात के जिन कागजों का लाभदायक रूप में उत्पादन किया जा सकता है उनमें एक निस्यन्दक पत्र (फिल्टर पेपर) भी है, जिसकी वैज्ञानिक और औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत मांग है। निस्यन्दक पत्र का उत्पादन इंग्लैण्ड और जर्मनी में हस्त प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके साथ ही, 'मेग' तथा 'वैक्सीन' के विसक्रमित निस्यन्दन अथवा फलों के रस व पेय पदार्थों के लिए निस्यन्दक-उपधान (फिल्टर पैड) और प्रयोगशालाओं में स्नेह, वसा आदि के निस्सारण के लिए निस्यन्दक थिम्बल भी बनाये जाते हैं। भारत में अब तक आयात किये गये निस्यन्दक पत्रों का उपयोग होता रहा है और हाल ही में आयात पर लगी रोक-थाम के फल स्वरूप वे दुष्प्राप्य हो गये हैं। निस्यन्दक पत्र के उत्पादन में विशेषता हासिल कर रहे हाथ कागज केन्द्र आगे आकर अब तक जिन भातों के कागजों का आयात किया जाता रहा है प्रायः उन सभी का उत्पादन कर बेच सकते हैं।

मानक-गुण

निस्यन्दक पत्र असज्जीकृत यानी साइजिंग नहीं किया हुआ विशुद्ध सैलूलोज से बना अवशोषक कागज होता है। सैलूलोज अत्यधिक विशुद्ध होनी चाहिए। उसमें कम से कम ९५ प्रतिशत ऐल्फा सैलूलोज होना चाहिए। इसमें थोड़ा-सा अपचायक गुणधर्म, ०.५ से अधिक नहीं, ६ और ८ के बीच पी एच अंक और थोड़ी-सा राख-अश होना चाहिए। ये कागज कई श्रेणी की

सरधरता में बनाये जाते हैं ताकि निस्यन्दन के समय विभिन्न आकार के अवक्षेप को रोक सकें। अतः निस्यन्दक पत्र के निर्माण में अन्य उच्च किस्म के कागजों की बनिस्बत अधिक तकनीक ज्ञान और सावधानी की जरूरत है। उत्पादन केन्द्र में लुग्दी के स्तर-नियंत्रण और तैयार माल के मानकीकरण हेतु एक छोटी प्रयोगशाला होनी ही चाहिए। इन केन्द्रों के प्रबन्धकों को कम से कम विज्ञान का स्नातक तो होना ही चाहिए और फिर उन्हें उच्च किस्म के कागज निर्माण तथा मानकीकरण में सामान्य तथा निस्यन्दक पत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

निस्यन्दक पत्र की मानक किस्में

निस्यन्दक पत्र के अधिकांश विदेशी निर्माताओं का विभिन्न किस्म के कागजों के वर्गीकरण का अपना मानक और तरीका है। तथापि सभी निस्यन्दक पत्र निम्न दो प्रकाशित मानक विशिष्टीकरण के अन्तर्गत आ सकते हैं (१) ए एस टी एम मानक विशिष्टीकरण (अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग मैटेरियल द्वारा प्रस्थापित मानक), और (२) तापी मानक विशिष्टीकरण (टेकनीकल एसोसिएशन फॉर पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्री, न्यूयॉर्क द्वारा प्रस्थापित मानक)। निस्यन्दक पत्र के मानकीकरण हेतु उपयोगी मानक विशिष्टीकरणों का संक्षिप्त विवरण इस लेख के अंत में दिया गया है।

ए एस टी एम मानक ने निस्यन्दक पत्र के लिए

निम्न श्रेणियाँ निश्चित की प्रकार १- सामान्य निस्पदन कार्य तथा गुणात्मक विश्लेषणात्मक के लिए उपयोग किया जानेवाला निस्पदक पत्र। इस किस्म को चार वर्गों में विभक्त किया जाता है (अ) मोटे और श्लेष्मिय अवक्षेपो के लिए, (आ) मध्यम आकार के अवक्षेपो के लिए, (इ) महीन अवक्षेपो के लिए, और (ई) महीन अवक्षेपो के लिए कड़े कागज। प्रकार २- परिमाणीय विश्लेषण के लिए उपयोग किया जानेवाला और वैसी लुग्दी से बना निस्पदक पत्र, जोकि राख-अश को कम करने के लिए अम्ल से दो बार धुला हो। इन्हे 'राख-रहित निस्पदक पत्र' भी कहते हैं। इसे भी पुनः चार वर्गों में बाटा जाता है- उ, ऊ, ओ और औ, जोकि सरन्धता में प्रकार १ के क्रमशः वर्ग अ, आ, इ और ई समान हैं।

उपकरण

निस्पदक पत्र के लिए जिन मूल सरजामो की आवश्यकता है, वे बहुत-कुछ खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के हाथ कागज उद्योग योजनान्तर्गत बड़ी और मध्यम किस्म की इकाइयों के लिए जो उपकरण निर्दिष्ट हैं, वैसे ही हैं। इन उपकरणों में उगलनेवाले किस्म का पाचक-यंत्र (डाइजेस्टर), एक शक्ति-चालित हॉलैण्डर लुग्दी कूटक, एक शक्ति-चालित कैलैण्डर रोल, एक बड़ा स्कू-प्रेस, कागज ऊठानेवाले साचे, वाट और कागज काटनेवाली मशीन शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस सरजाम की आवश्यकता होगी उसमें योग्य लुग्दी धुलाई के लिए हायड्रो-एक्स्ट्रैक्टर (जैसा कि कपडा धुलाई उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है) और लुग्दी के अम्लीय शोधन के लिए अम्लभेद्य एपोक्सी-रेजिन पेट से रंगा लकड़ी का वाट अथवा पोलिथीन टैंक की जरूरत होगी। निस्पदक पत्र के निर्माण में अधिक मात्रा में शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अन्तिम प्रक्रियाओं में आसुत जल की। आसुत जल तैयार करने के लिए जल भभका की जरूरत पड़ती है, जिसकी क्षमता तीन से पाच गैलन जल प्रति

घटा बिजली अथवा छोटे-से प्रेसर-बायलर से प्राप्त वाष्प से गर्म करने की होनी चाहिए।

आसुत जल के बदले, जिसे तैयार करना खर्चीला है, खनिज निकाले जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जल को खनिज रहित करनेवाले उपकरण की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से नल का सामान्य मृदु जल केशन्स और एनियन्स दूर कर, जोकि उपकरण में लगे जियोलाइट्स, विशेष रेजिन, कार्बियोन आदि द्वारा सोख लिये जाते हैं, शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। कागज हाथ से उठाया जाता है, लेकिन ताव का मानक वजन और मोटापन सुनिश्चित करने के लिए 'पोर मोल्ड' किस्म के वाट का इस्तेमाल करना जरूरी है, जैसा कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसन्धानशाला में एक विकसित गया है। इस वाट में पानी की बहुत बचत होती है, जोकि जहा आसुत जल इस्तेमाल किया जाता है वहा के लिए अत्यावश्यक है। कागज सुखाने के लिए एक विशेष कमरे की जरूरत होगी, जहा कि तार पर लटका कर हवा से कागज सुखाने होंगे। सामान्य पद्धति से दीवाल पर कागज सुखाने का परिणाम यह निकलता है कि उसका राख-अश बढ़ जाता है, जिस कारण इसे निस्पदक पत्र के लिए नहीं अपनाया जा सकता।

निर्माण प्रक्रिया

निस्पदक पत्र निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में सफेद कपड़े की कतरनो (अथवा गजियो की कतरनो) का उपयोग किया जाता है, जोकि शुद्ध सूती वस्त्रों से प्राप्त की जाती हैं और यथासम्भव वे एक ही किस्म और मूल की होनी चाहिए। कपास का भी इस्तेमाल किया जाता है। कतरना को हाथ से चुनना होगा ताकि रगीन टुकड़े तथा अन्य किस्म के प्राकृतिक और मनुष्य निर्मित वस्त्र टुकड़ों को निकाला जा सके। वैज्ञानिक इस्तेमाल हेतु तैयार किये जानेवाले निस्पदक पत्र के लिए श्वेतीकरण की हुई कतरने ही चाहिए। तथापि

औद्योगिक निस्यदन के लिए भूग निस्यदक पत्र सफेद और रंगीन कतरनों को मिला कर बनाया जा सकता है। चुनिन्दा कतरनों को पाचक यंत्र में ५ प्रति शत (चिथड़ों के वजन का) दाहक मोडे के साथ दो घंटे उबालने में अशत धोते हैं और तब अवस्थामें ८ से १० मिनट तक अम्बार लगाते हैं। इस अवधि में छोटे-छोटे फुफुदे उग आते हैं, जोकि रेशों को मुलायम कर देते हैं। फिर कतरनों को नल-जल में अच्छी तरह धोते हैं, हायड्रो एक्स्ट्रेक्टर के जरिये उनका जल निकालते हैं और मुखाते हैं। फिर उनके और छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं, जो करीब १ वर्ग इंच के हो जाते हैं, और हॉलैण्डर बीटर में नल-जल मिला कर बेलन के सामान्य दबाव पर, बिना कूटक योगजों अथवा रसायनों के उपयोग के, कूटते हैं। कूटने की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि लुग्दी स्कापर-रीम्लर मुकनता परीक्षक में परीक्षण किये जाने पर करीब ३० एम्. आर. मुकनता न दिखाने लगे।

इस शुद्धता की लुग्दी वैसे निस्यदक पत्र तैयार करती है जोकि मोटे और श्लेपीय अवक्षेपों को छानने के लिए आवश्यक है (वर्ग अ और उ)। महीन अवक्षेपों को छानने के लिए लुग्दी को एस आर के और उच्च डिग्री तक कूटना पड़ेगा। इस कार्य के लिए कोई मानक निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि किस हद तक कुटाई होगी और शुद्धता रहेगी, वह कई कारकों पर निर्भर करेगी और उनका निर्णय और मानकीकरण उत्पादन केन्द्र में परीक्षण दल बना कर तथा इस तरह तैयार किये गये पत्र का ए एस टी एस मानक से सरधता के लिए परीक्षण कर करना पड़ेगा। कूटी हुई लुग्दी बाद में धोयी जाती है और ५ से ७ प्रति शत ब्लिचिंग पावडर के साथ श्वेत की जाती है। श्वेतीकरण टब या टकी में करना अच्छा है। श्वेतीकरण के बाद और पूर्णत धोने के पूर्व लुग्दी को ०.१ प्रति शत हायड्रोक्लोरिक एसिड के साथ शोधन करने की जरूरत है, जोकि रेशों के राख अश को कम कर देता है।

राख-रहित निस्यदक पत्र (प्रकार २) के निर्माण के

लिए दोहरी अम्लीय धुलाई होनी चाहिए, जिसमें दूसरी धुलाई एपोक्सी-रेजिन से रगी लकड़ी की टकी अथवा पोलिथिन टकी में बहुत ही हल्के हायड्रोक्लोरिक एसिड और हायड्रोक्लोरिक एमिड का घोल मिला कर होनी चाहिए। तैयार पत्र को सुखाने के बाद उसे सामान्य तीव्रतावाले सल्फूरिक एसिड में थोड़े समय सुखाने से और फिरसे सुखाने के पूर्व जल से अच्छी तरह धोने में कड़ा निस्यदक पत्र मिलता है। आम्ल-शोधित लुग्दी को प्रथम नल-जल से और अन्तत आमुत (अथवा खनिज रहित) जल से तब तक धोते हैं जब तक कि वह क्लोराइड रहित न हो जाय। क्लोराइड का अश जानने के लिए सिल्वर नाइट्रेट घोल परीक्षण करते हैं। पी. एच. सूचकांक में इसकी नकारात्म प्रतिक्रिया होनी चाहिए।

कागज उठाने का काम हाथ में किया जाता है और उस में पोर-मोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ५ प्रति शत से अधिक वजन और मोटापन विभिन्नता का कागज न उठे। इस कार्य के लिए आसुत अथवा खनिज रहित जल अत्यावश्यक है। साचे में फोस्फर-ब्रॉज-स्क्रीन लगा होना चाहिए। उठाये गये गीले कागज के तावों के बीच अच्छी तरह धुले कपड़े अथवा फैल्ट रहते हैं। स्कूप्रेस में १०० से १५० तावों को अच्छी तरह दबाते हैं। उसके बाद उन्हें कपड़े (अथवा फेन्ट) सहित लकड़ी अथवा प्लास्टिक किल्पो के जरिये तार पर लटका देते हैं। सूखे कागजों की कैलेंडरिंग और कटाई सामान्य तरीके से की जाती है। निस्यदक पत्र न सिर्फ ५०० तावों (माग के अनुसार आकारों में) के रीमों में बिकते हैं बल्कि विभिन्न मानक व्यास के गोल आकारों में १०० ताव के कूट के बक्सों में भी बिकते हैं। गोल आकार में काटने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। एक बैच तैयार हो जाने पर तब तक के लिए उसे अलग रख दिया जाता है, जब उसके नमूने पर प्रयोगशाला में परीक्षण न हो जाये। अन्तिम पैकिंग में बक्स पर बैच नंबर, श्रेणी, कागज का आकार (या गोलाई का व्यास) और राख-रहित

पत्रो के मामलो मे उसके नमूने मे प्राप्त राख अश की सही मात्रा दर्ज होती है।

विशिष्टीकरण

सामान्य तौर पर किस्म १ के वर्ग अ निस्यदक पत्रो की अन्य पत्रो से बहुत अधिक माग है। जो उत्पादन केन्द्र निस्यदक पत्र मे विशिष्टीकरण करते हैं, उन्हें प्रथम इस श्रेणी का पत्र अच्छे स्तर पर बनाना ही चाहिए। जोरदार विश्वास हो जाने के बाद उच्च और राख-रहित श्रेणी के पत्र तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। फिल्टर थिम्बल का उत्पादन (जोकि प्रकार १ के वर्ग अ के समान है) आसान है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय अनुसंधानशाला में विशेष साचा तैयार किया गया है। कीटाणु रहित और अन्य निस्यदन के लिए निस्यदक उपधानो का उत्पादन अधिक कठिन है और इसके लिए परीक्षण की विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है, जिसमे कीटाणु सवर्धन का उपयोग किया जाता है। यह कार्य अच्छा अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही करना चाहिए। कीटाणु अश्वेक्ष निस्यदक उपधान सामान्यतया या तो शुद्ध एसबेस्टस लुग्दी से बनाये जाते हैं अथवा सैलूलोज और एसबेस्टस लुग्दी को मिला कर, ताकि वे अधिक गीलापन सह सके।

नियंत्रण प्रयोगशाला

निस्यदक पत्र का निर्माण करनेवाले प्रत्येक केन्द्र के पास नियंत्रण और मानकीकरण कार्य के लिए उपकरण और कार्यकर्त्ताओ से सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए। निस्यदक पत्र मानकीकरण के लिए महंगे भौतिक परीक्षण यंत्रो की आवश्यकता नहीं है, जिनका इस्तेमाल लिखने और छपाई के कागजो के लिए किया जाता है। परन्तु उनमे भी अपवाद है—(१) गीलापन, स्फूटन सामर्थ्य जाचने के लिए ग्लेन स्फूटन सामर्थ्य परीक्षक, (२) कागज की मोटाई नापने के लिए डॅड वेट डेस्क माइक्रोमीटर, (३) लुग्दी के लिए स्कॉपर रीगलर मुक्तता परीक्षक, और (४) कीरनर

किस्म का विघटक। हमारे देश मे तैयार किये गये औजार आसानी से ताप्पी मानक के मद (१), (३) और (४) का निर्माण कर सकते हैं। अन्य परीक्षणो की तरह यह उपकरण प्रयोगशाला मे इस्तेमाल किया जानेवाला शीशे का बर्तन होता है, जोकि सहज ही बै ाया जा सकता है और रसायन भी सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। उपकरण का विवरण प्रकाशित मानको मे दिया गया है।

प्रकाशित मानक

निस्यदक पत्र के लिए निम्न मानक विशिष्टीकरण सन्दर्भ के लिए अत्यावश्यक है। प्रत्येक के अतर्वस्तु की सक्षिप्त जानकारी यहां दी जा रही है।

१ ए एस. टी. एस मानक डी ११००-५२ विशिष्टीकरण का उपयोग रसायन विश्लेषण मे इस्तेमाल किये जानेवाले निस्यदक पत्रो के लिए किया जाता है। (इसका विवरण ऊपर दिया गया है)। गोलाई के लिए मानक व्यास भी दिये गये हैं। ऐल्फा सैलूलोज कापर नम्बर, पी एच वैल्यू, और राख अश की सीमाएं भी निर्धारित हैं। नमूना बनाने की विधि भी बतायी गयी है। अवक्षेपो के छनने, जल प्रवाह का समय, राख अश और गीलापन स्फूटन सामर्थ्य निश्चित करने के तरीके भी बताये गये हैं और विभिन्न श्रेणीयो की सीमाएँ निर्धारित हैं।

२ ताप्पी मानक टी-४२९ एम-४८ यह निस्यदक पत्र लुग्दी मे ऐल्फा, गामा, बीटा, सैलूलोज की मात्रा निश्चित करने का तरीका बताता है।

३. ताप्पी मानक टी-४३० एम-५२ यह निस्यदक पत्र लुग्दी का कापर नम्बर निश्चित करने का तरीका बताता है।

४ ताप्पी मानक टी-४३५ एम-५२ यह पत्रो मे हायड्रोजन सकेन्द्रण (पी एच) निश्चित करने का तरीका बताता है।

बम्बई ५ दिसम्बर १९६१

ग्रामीण औद्योगीकरण के लाभ

भारत भूषण कंसार

वर्तमान दुरावस्था में सुधार लाने के लिए ऐसा कोई भी निदान प्रभावक नहीं हो सकता जिसमें कृषि क्षेत्र की अतिरिक्त जन-शक्ति को लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के काम-धंधों की व्यवस्था न हो।

आधुनिक उद्योग जगत राकेट की गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसी अवस्था में क्या हमारे लिए यह उचित है कि हम अपनी पुरानी परम्परागत बैलगाड़ी से ही चिपके रहे? क्या हमें भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाना पसन्द है? हमारे आयोजको, अर्थशास्त्रियों और यहां तक कि सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये प्रश्न सर्वाधिक रूप से उठते हैं। औद्योगिक विकास के इतिहास से पता चलता है कि पश्चिम के उन्नत देश यात्रीकरण से आगे बढ़े हैं। तब प्रश्न उठता है कि क्यों न भारत भी रूढ़िवादिता की जजीर तोड़ फेंके और जमाने की रफ्तार के साथ आगे बढ़े? तथापि, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारत एक अल्प-विकसित देश है, जिसमें घोर गरीबी, निरक्षरता, निम्न जीवन-स्तर, बचत और विनियोग की अल्प दर, कुशल तथा सक्षम श्रमिकों का अभाव, प्रभावक मौंग की कमी और अत्यधिक जन-संख्या का दबाव है।

सन् १९६१ की जनगणना के प्रतिवेदन से भविष्य के सम्बन्ध में एक सकटपूर्ण संकेत मिलता है। सन् १९६१ में सप्ताह की जन-संख्या तीन अरब थी, जिसमें से भारत की आबादी ४३ करोड़ ८० लाख थी। इस प्रकार हम भारतवासी विश्व जन-संख्या के एक-सप्ताश हैं। भारत का भूमि-क्षेत्र सप्ताह के समस्त भूमि-क्षेत्र का २४ प्रतिशत है और जन-संख्या सप्ताह की आबादी का १४.५ प्रतिशत। अतः भूमि-क्षेत्र के आधार पर भारत में जन-संख्या का भार सप्ताह के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। विश्व की जन-संख्या १९५० में २ अरब

५० करोड़ थी, वहीं गत दशक में बढ़ कर तीन अरब हो गयी। इस प्रकार २० प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके समक्ष उक्त अवधि में भारत की जन-संख्या में २२ प्रतिशत वृद्धि हुई।*

योजना आयोग का मत

इस प्रकार देश में आर्थिक तथा सामाजिक हालातों को देख कर कोई भी यह कह सकता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्था से ठीक विपरीत दिशा में है। हमारी आर्थिक समस्याओं का एकमात्र हल ग्रामीण औद्योगीकरण का मार्ग अपनाने में निहित है, जोकि हमारे विशाल अतिरिक्त श्रम, उत्पादन के अयोग्य साधनों तथा अल्प पूँजी स्रोतों के अनुकूल है, और इस प्रकार किसान को गैर-मौसमी, अश कालीन और पूरक रोजगारी प्रदान करता है। इसमें उसकी आय भी बढ़ेगी और आम जखुरत की उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। योजना आयोग भी ग्रामीण उद्योगों के विकास को बहुत महत्व देता है जोकि इस सम्बन्ध में पहली, दूसरी और तीसरी योजना में किये गये निम्न लिखित उल्लेखों से परिलक्षित होता है।

प्रथम योजना “इस देश की कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था में लघु स्तरीय उत्पादन के महत्व पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता हो। जनतांत्रिक तरीके

* अखिल भारत कॉंग्रेस कमेटी की पत्रिका आर्थिक समीक्षा के जुलाई १९६३ के अंक में ससद सदस्य श्रीरामा रेड्डी का लेख—भारत में कृषि विकास।

से आर्थिक विकास के लिए यह परमावश्यक है कि अधिकारों के स्रोतों और उत्पादन के साधनों का विस्फुरण हो, जिससे लोगों में नयी शक्ति उत्पन्न होगी और वे योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था के संचालन में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे, फिर चाहे उनका कार्य-क्षेत्र कितना ही छोटा क्यों न हो। अब यह व्यापक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है कि अत्यधिक केन्द्रीकरण—जोकि अभिक्रम और उद्यमशीलता को मृतप्राय बना देता है—की खामियों को दूर करने के लिए स्थानीय स्वशासन तथा आर्थिक शक्तियों के विस्फुरण का होना अत्यावश्यक है। लघु उद्योग सहायक अथवा वैकल्पिक काम-धंधे प्रदान करने तथा स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करने या स्थानीय बाजारों को माल की पूर्ति करने के लिए भी अत्यावश्यक है।”

द्वितीय योजना: “ग्रामीण तथा लघु उद्योग अपने विभिन्न रूपों में विभिन्न आर्थिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय आयोजन दोनों में ही अभिन्न व स्थायी अंग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है रोजगारी के अवसरों का विस्तार करना, आय की वृद्धि करना तथा जीवन-स्तर ऊँचा उठाना और एक सन्तुलित तथा समन्वित ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना। आवश्यक रूप से ही ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत उद्योगों पर तुरन्त ध्यान देना पड़ेगा।”

तृतीय योजना. “प्रथम और द्वितीय योजना में रोजगारी विस्तार, अधिक उत्पादन और अधिक न्याय सगत वितरण की दिशा में ग्राम तथा लघु उद्योगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। तृतीय योजना में और भी अधिक विस्तृत व व्यापक कार्य पूरे करने के सन्दर्भ में उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी प्राविधिक परिवर्तनों की गति इस प्रकार नियमित करनी पड़ेगी कि दीर्घ स्तरीय प्राविधिक बेरोजगारी और उसके फलस्वरूप लाखों लोगों को होनेवाली तकलीफों व कठिनाइयों से बचा जा सके। इसलिए खादी और ग्रामोद्योगों की

समस्याओं पर निरन्तर विचार करते रहने की और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में विकेन्द्रित उद्योगों को एक अत्यावश्यक तथा स्थायी तत्व के रूप में पूर्ण क्षमता प्राप्त करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।”

लघु उद्योगों की बहुमुखी भूमिका

जिन आधारों पर लोग ग्रामीण उद्योगों के विकास कार्यक्रम का समर्थन अथवा विरोध करते हैं, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है

अ जो इन उद्योगों के विकास के पक्ष में हैं वे कह सकते हैं कि मौजूदा अवस्थाओं में, जोकि अधिकांशतः अर्थ-व्यवस्था के अल्प विकसित स्वरूप को और जिस संक्रमण की प्रक्रिया से होकर वह गुजर रही है उस पर प्रकाश डालती है, लघु उद्योगों के अनेक कार्य हैं, जैसे (१) रोजगारी की दृष्टि से देखने पर वे पूर्ण अथवा अल्प समय का रोजगार और चन्द परिस्थितियों में आर्थिक दृष्टि से सकट में पड़े लोगों को राहत प्रदान करते हैं, (२) उत्पादन के विचार से वे बड़े उद्योगों के उत्पादन के पूरक हैं और इस प्रकार उपभोक्ता सामानों तथा लघु उत्पादकों की वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करते हैं, (३) वे सम्भवतः अल्प विकसित देश में अत्यन्त दुर्लभ स्रोत—मनलब यह कि पूँजी—का लाभदायक रूप से उपयोग करने में सहायता प्रदान करते हैं, और (४) सृजनात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति में सुविधा प्रदान करने और स्वतंत्र कारीगरों तथा लघु उद्योग-पतियों की परम्परा को कायम रखने तथा मजबूत बनाने के लिए उनका उपयोगी स्थान है।

आ जो लोग ऐसे उद्योगों के पक्ष में नहीं हैं वे कहते हैं कि (१) उनमें निम्न कोटि तथा कई मामलों में तो अप्रचलित व पुरानी उत्पादन तकनीकों का व्यवहार होता है और यह कि पूँजी की प्रति इकाई के उपयोग से प्राप्त उत्पादन की दृष्टि से देखने पर यह कथन भी भ्रामक मालूम पड़ता है कि ये उद्योग पूँजी कालाभदायक रूप में उपयोग करते हैं, (२) इन उद्योगों से उत्पादन में जो योगदान मिलता है उसके लिए किमी हद तक राष्ट्र

को कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि कम कुशल उत्पादन प्रणाली के लिए बेहतर तथा अधिक कुशल उत्पादन प्रणाली का परित्याग किया जाता है, (३) इन उद्योगों में कर्मियों को अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक स्वीकार करना पड़ता है, (४) आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया से लोगों का अनुकूलतम, न कि अधिकतम, उपयोग सुनिश्चित होता है, इसलिए यह आशा करना ठीक नहीं होगा कि प्रगति की अवस्थाओं के अन्तर्गत प्रत्येक स्रोत का पूर्ण उपयोग होगा, और (५) अस्थायी बेकारी तथा अपने पैरो पर खड़े होने में असमर्थ अक्षम उद्योगों का अवसान आदि प्रगति पथ में 'मील के पत्थर' हैं।

व्यावहारिक दृष्टिकोण बांछनीय

इस विवाद में एक ऐसा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया उचित होगा जो निम्न बातों के अनुकूल हो।

(१) एक करोड़ में अधिक व्यक्ति, पूर्णतः अथवा अंशतः अपनी आजीविका के लिए लघु उद्योगों पर निर्भर करते हैं। इस बड़ी सख्या में लोग सरलता से दूसरे अधिक लाभकारी उद्यम में नहीं लगाये जा सकते और इस प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रयास किया गया तो उसके परिणाम-स्वरूप अनेक लोगों की रोजगारी ही नहीं छिन जायेगी, बल्कि उससे इस उद्योग में लगी कुशलता और पूँजी की बहुत बड़ी मात्रा में हानि भी होगी, (२) तकनालॉजी के परिवर्तनों से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए यथोचित कार्यवाही का उत्तरदायित्व राज्य सत्ता को लेना पड़ेगा, (३) ग्रामीण उद्योग ऐसे साधनों में से हैं जिनके द्वारा जन-समूह के कुछ ऐसे तबकों के लिए काम का अवसर प्रदान किया जा सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है जैसे खेत मजदूर, शिक्षित बेकार, विस्थापित लोग आदि, (४) यह तथ्य कि बहुत कम आय होने के बावजूद बहुत बड़ी सख्या में लोग सूत कटाई जैसे हल्के औद्योगिक कामों को भी अपना लेते हैं, इस बात पर प्रकाश डालता है कि फिलहाल कोई अधिक लाभदायक रोजगारी का जरिया तुरत-फुरत उपलब्ध नहीं है, और (५) लघु

उद्योगों में ३० लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करनेवाला हाथ करघा उद्योग शायद सबसे बड़ा क्षेत्र है और सम्भवतः वह उत्पादन में भी सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि घरेलू उपभोग के लिए कुल वस्त्रोत्पादन का ३० प्रतिशत हाथ करघों पर तैयार होता है।

उपर्युक्त व्याख्या का तात्पर्य यह है कि इस रोग के लिए कोई भी ऐसी दवा कारगर नहीं होगी जिसमें विविध उद्यमों का, जिनमें कृषि से अतिरिक्त जन-सख्या हटा कर जीवन-यापन के अन्य साधन प्राप्त करने की ओर प्रेरित की जा सके, समावेश न हो।

लघु स्तरीय उद्योग

बड़े तथा ग्रामोद्योगों के मध्य अन्य उद्योग हैं जो साइकल, रेडियो के पुर्जों, सामान्य विद्युत सामान, चाकू-छुरी, ताले, बटन, कृषि मरजाम आदि बनाते हैं। ये उद्योग यंत्र, पूँजी और कच्चे माल का लघु स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन्हें लघु स्तरीय अथवा लघु उद्योग कहा जाता है। और फिर, देश भर में ऐसे कारीगर और कलाकार फैले हुए हैं जो अपने हाथों से बहुत सुन्दर सामान बनाते हैं। इसमें धातु के बर्तन, गुडियों और खिलौने, पत्थर और सगमरमर पर खुदाई, कलात्मक मिट्टी-बर्तन, चटाइयाँ और कालीन तथा फैशनवाली चमड़े की वस्तुएँ सम्मिलित हैं। ये हमारे चन्द मूल्यवान शिल्पों में हैं।

संक्षेप में, ये मुख्यतः स्थानीय बाजारों के लिए स्थानीय कच्चे माल से और वह भी साधारण तकनीकों का प्रयोग कर सामान तैयार करते हैं। वस्तुतः यह तय करने के लिए कि अमुक उद्योग बड़ा उद्योग है या छोटा, अनेक कसौटियाँ सुझायी गयी हैं। लघु उद्योग का तात्पर्य है एक ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें शक्ति का प्रयोग किया जाता हो और ५० से कम व्यक्ति काम करते हो अथवा जिसमें विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता हो और १०० से कम व्यक्ति काम करते हो तथा उसकी सम्पत्ति पाँच लाख रुपये से अधिक न हो। हालाँकि हमें, इस परिभाषा में संशोधन किया गया है, जिसमें कर्म-

चारियों की सख्या का जिक्र नहीं है और कसौटी यह रखी गयी है कि सकल अचल पूँजी (ग्रॉस फिक्सड कैपिटल) पाँच लाख रुपये या उससे कम हो। यह इसलिए किया गया है कि लघु उद्योग द्वारा प्रदत्त रोजगारी की मात्रा पर से बन्धन हटाया जा सके। इस प्रकार के उद्योग का मुख्य उद्देश्य है रोजगारी में वृद्धि करना और इसलिए यह सोचा गया है कि काम में लगे कर्मचारियों की सख्या पर से प्रतिबन्ध खत्म किया जाय। अब लघु उद्योग का अर्थ है पाँच लाख रुपये अथवा उससे कम अचल पूँजी सम्पत्तिवाले सभी औद्योगिक संगठन।

उपर्युक्त परिभाषा में एक बहुत बड़ा समूह आ जाता है जो स्वयम् विजातीय है अर्थात् उसमें कई तरह के उद्योग आते हैं लघु स्तरीय उद्योगों को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, कुटीर उद्योग, जो परम्परागत उत्पादनों के लिए परम्परागत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये गाँवों में स्थित हैं और घरेलू उद्योगों के रूप में चलाये जाते हैं (जिनमें मजदूरी पर बहुत कम या कोई श्रमिक नहीं रखा जाता)। ये मुख्यतः अपना कच्चा माल स्थानीय स्रोतों से प्राप्त करते हैं और अपने उत्पादनों को स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। सामान्यतः ये उद्योग ग्रामीण, घरेलू तथा स्थानीय हैं और तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए। द्वितीय मुख्य प्रकार के लघु स्तरीय उद्योग पूर्णतः भिन्न हैं। ये आधुनिक लघु अभियंत्रण ('इजीनियरिंग') और रासायनिक उद्योग हैं जो धातु के बर्तन, साइकल के सामान, सिलाई की मशीनें, औजार, दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की जानेवाली पत्ती, इलेक्ट्रिक मोटर, चश्मों के फ्रेम और अन्य अनेक आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। घरेलू उद्योगों से विपरीत ये उद्योग सामान्यतः शहरों में स्थित हैं। इनमें मजदूरी पर श्रमिक रखे जाते हैं और प्रायः दूर से मगाये गये इस्पात तथा रसायनों जैसे कच्चे माल का इस्तेमाल होता है और इनके उत्पादनों की बिक्री बहुत दूर तक के क्षेत्रों में होती है।

इन दो श्रेणियों के बीच माध्यमिक उद्योग हो सकते हैं, जो प्रायः परम्परागत तकनीक का इस्तेमाल करके

कमोबेश आधुनिक वस्तुएँ बनाते हैं, जिनमें जूते, फर्नीचर, ईंटे, मोमबत्तियाँ और इम तरह के अन्य सामान हैं। ये मुख्यतः हाथ से बनाये जाते हैं न कि मशीन से। ये भी श्रम-प्रधान, पूँजी बचतकारी तकनीकें हैं।

इस प्रकार लघु स्तरीय उद्योग का क्षेत्र तकनीक, उत्पादन और इसके द्वारा उत्पन्न सामानों के प्रकार की दृष्टि से एक विषम क्षेत्र है। तथापि, प्रायः ये श्रम-प्रधान हैं और इन्हें बहुत कम पूँजी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु इनकी श्रम तथा पूँजी सघनता में भी बहुत अधिक भिन्नता है। इन उद्योगों में अनेक प्रकार की क्रियाशीलताएँ सम्मिलित हैं। इनमें खाद्य वस्तुओं, तबाकू के सामान, ऊन, रेशम और कपास के वस्त्र, लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएँ, चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएँ, मिट्टी के बर्तन, ईंटे, शीशे तथा धातु की वस्तुएँ बनाना सम्मिलित हैं।

संगठन की वैयक्तिक विशेषता

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आकड़ों में कुछ समायोजन करने के बाद श्री धर और लिण्डाल* ने यह हिसाब लगाया है कि इस वर्ग में घरेलू उद्योग प्रधान रहे हैं और उनकी सख्या ५० लाख तथा उनमें रोजगार पानेवाले लोगों की सख्या १ करोड़ २० लाख रही है। पाँच से नौ व्यक्तियों को काम देनेवाले प्रतिष्ठानों की सख्या १ लाख ३० हजार और उनमें रोजगार पानेवाले लोगों की सख्या नौ लाख दस हजार रही, दस से उन्नीस व्यक्तियों को काम देनेवाले प्रतिष्ठानों की सख्या ४३ हजार और उनमें रोजगार पानेवाले व्यक्तियों की सख्या पाँच लाख रही, बीस से उनचास व्यक्तियों को काम देनेवाले १८ हजार प्रतिष्ठान थे, उनमें काम करनेवाले लोगों की सख्या पाँच लाख साठ हजार रही, और ५० से ९९ तक लोगों को काम देनेवाले प्रतिष्ठान ४,६६० थे और उनमें काम करनेवाले लोग ३ लाख ४० हजार थे।

* पी एन धर और एच एफ लिण्डाल, दि रोल ऑफ स्माल इण्टर प्राइजेज इन इण्डियन इकनॉमिक डेवलपमेण्ट बम्बई, १९६१, के पृष्ठ ७ पर दी गयी तालिका देखिए।

कुटीर और लघु स्तरीय उद्योगों का विशिष्ट स्वरूप है, बड़े उद्योगों के प्रमुख रूप में अवैयक्तिक प्रबन्ध के विपरीत इनके संगठन तथा प्रबन्ध में वैयक्तिकता का होना। कुटीर उद्योग सामान्यतः पारिवारिक आधार पर चलाया जाता है तथा लघु उद्योग स्वामित्व के आधार पर और कभी-कभी साझेदारी के तौर पर संगठित किया जाता है, किन्तु शायद ही वह कभी कम्पनी के तरह के संगठन के आधार पर चलाया जाता हो। अधिकांश उद्योग का मालिक खुद ही प्रबन्धक, तकनीज्ञ और वित्त दाता होता है। स्वामित्व तथा प्रबन्ध अधिकांश मामलों में वस्तुतः एक सम होता है। इन उद्योगों के मालिक स्वतन्त्र रहते हैं। इन उद्योगों के संचालन के लिए नियम और विधियाँ संगठित उद्योगों के नियम और विधियों से कम हैं। इस तरह यह प्रणाली कानूनी रोक-थाम से मुक्त है। यह शीघ्र तथा त्वरित कार्यान्वय के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है।

तथापि, उत्पादन की अधिक लागत के परिणाम स्वरूप इन उद्योगों की प्रतियोगिता की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके सिवाय मध्यस्थ व्यापारी अथवा दलाल (मिडलमैन, ट्रेडर) का बहुत अधिक लाभार्थ भी जोड़ा जा सकता है। वास्तविक उत्पादक को दोनों तरह से हानि उठानी पड़ती है—कच्ची सामग्री तथा अन्य मदों के लिए उसे अधिक कीमत देनी पड़ती है और तैयार माल का उसे अलाभकारी मूल्य मिलता है। लागत कम करने, कार्यक्षमता बढ़ाने और उसके द्वारा प्रतियोगिता की शक्ति में अभिवृद्धि करने के लिए सभी दिशाओं में एक साथ प्रयास करने से ये कठिनाइयाँ हल की जा सकती हैं तथा अवरोध दूर किये जा सकते हैं।

सरकारी नीति और प्रयास

राष्ट्रीय सरकार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू से ही प्रयत्नशील है। प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव (१९४८) में उनके महत्व पर जोर दिया गया

था और उनके लिए सरकारी सहायता का आश्वासन दिया गया था। प्रथम पंच वर्षीय योजना में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए ३० करोड़ रुपये (सार्वजनिक विभाग के कुल परिव्यय का १३ प्रतिशत) व्यय करने का प्रावधान रखा गया। द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उनके महत्व को दोहराया गया और भारत की अर्थ-व्यवस्था में उनके विशेष महत्व पर जोर दिया गया। ग्राम तथा लघु उद्योग (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) समिति ने विस्तार में वेतर्क पेश किये, जिनके आधार पर इन उद्योगों को न्यायसंगत बनाया गया है। उसने दूसरी योजना में २ अरब ६० करोड़ रुपये के व्यय का कार्यक्रम सुझाया और बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशों की। फोर्ड फाउण्डेशन दल, जापानी दल और अनेक कार्यकारी दलों तथा समितियों ने इन उद्योगों के कार्य की भी जाँच की है। इन संगठनों ने भी इन उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ाने और वित्तीय स्थिति अच्छी करने के लिए सिफारिशों की हैं।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए २ अरब रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय का ४१ प्रतिशत) का साहसिक कार्यक्रम शामिल किया गया। उनकी प्रतियोगितात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक तथा अन्य अनेक प्रकार के कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया। तृतीय योजना में ग्राम तथा लघु उद्योगों के कार्यक्रम के लिए कुल २ अरब ६४ करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है, जबकि द्वितीय योजना में १ अरब ८० करोड़ रुपये से कम व्यय होने का अनुमान लगाया जाता है।

आशा है कि दो दशकों से भी अधिक समय की अवधि तक प्राप्त प्रश्रय तथा सहायता के बाद विकेंद्रित उद्योग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकेगा।

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) . ११ दिसम्बर १९६३

मैसूर के गाँवों में प्रचलित काम-धंधे

बन्दार चकण शेट्टी

मैसूर राज्य के बेल्गारी जिले में १९५७-५८ में दो गाँवों का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यद्यपि दोनों गाँव एक-दूसरे के बहुत निकट हैं, तथापि कोई खास गैर-खेतिहर काम न होने की वजह से एक के काम-धंधे के स्वरूप में बहुत ही कम परिवर्तन आया है, जबकि दूसरे गाँव में प्रचलित काम-धंधों के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, जोकि एक बृद्धिशील गैर-खेतिहर विभाग के साथ द्रुत गति से एक कस्बे के रूप में विकसित हो रहा है।

मैसूर राज्य के बेल्गारी जिले में कुछ गाँवों का, मीण क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के उद्देश्य से पूना स्थित 'गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स' के तत्वावधान में एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया। जिन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से दो गाँवों के नाम हैं हगरी बोम्बन हल्ली जिसे लेख में आगे ह बो हल्ली कहा जायेगा, और चित्रपल्ली। गाँवों में प्रचलित काम-धंधों का अध्ययन करना सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण विषय था। प्रस्तुत लेख में इस काम-धंधे के स्वरूप पर विचार किया गया है। ह बो हल्ली और चित्रपल्ली होसपेट से २५ मील की दूरी पर एक-दूसरे के पड़ोसी गाँव हैं, लेकिन अनेक बातों के सम्बन्ध में उनमें भिन्नता पायी जाती है।

सर्वेक्षण के वक्त ह बो हल्ली में कुल आबादी १,०१८ थी। चित्रपल्ली काफी छोटा है। उसमें जन-संख्या, सर्वेक्षण के समय मात्र २८८ थी। तालिका १ में परिवारों का मुख्य पेशे के अनुसार विभाजन प्रस्तुत है।

निम्न तालिका से स्पष्ट है कि चित्रपल्ली की अर्थ-व्यवस्था कृषि-प्रधान है, जबकि ह बो हल्ली में ६० प्रति शत लोगो के जीविकोपार्जन का जरिये इतर खेतिहर धंधे हैं। कृषि के सम्बन्ध में एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गाँवों में काश्तकार कृषकों की संख्या बहुत कम है। ह बो हल्ली में ४०७ परिवार खेती करते हैं। उनमें से केवल १० परिवार ही काश्तकार कृषक हैं।

चित्रपल्ली में भी इनका अनुपात तीन प्रति शत से अधिक नहीं है। तथापि, खेतिहर मजदूरों का प्रातिशत्य दोनों ही गाँवों में पर्याप्त अधिक है। ह बो हल्ली में जितने व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हैं उनमें ३७ प्रति शत और चित्रपल्ली में २६ प्रति शत व्यक्ति कृषिक श्रमिक हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ह बो हल्ली में गैर-खेतिहर विभाग का आकार सामान्यतः काफी बड़ा है। इस विभाग में मुख्यतः मूंगफली के छिलके उतारने और तेल पेराई तथा बुनाई का काम करनेवाली पाँच-सात मिलें हैं, जिनसे लगभग ५० परिवारों को रोजगारी

तालिका १

पेशेदार विभाजन

पेशा	परिवारों का प्रातिशत्य	
	ह बो हल्ली चित्रपल्ली	
कृषि व प्राथमिक उत्पादन	४० १	९१ १
खाद्य सामग्री व कपड़े आदि का प्रशोधन व उत्पादन	२५ ५	३ १
वाणिज्य	९ ३	२ ८
परिवहन	२ ६	—
निर्माण कार्य आदि	६ ३	१ ०
स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम प्रशासन आदि	५ ४	० ३
अन्य सेवाएँ	१० १	१ ७
योग	१०० ००	१०० ००

मिलती है। कई परिवार वाणिज्य-गाव में व्यवस्थित बाजार हैं-और निर्माण कार्य भी करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह भारत के वैसे गाँवों में से है, जो लघु उद्योगों और व्यावसायिक काम-धंधों के जगिये ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तथापि, उल्लेखनीय बात यह है कि वास्तव में हूँ बो हल्ली की विकास प्रक्रिया ने पास के गाव चित्रपल्ली की अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं डाला, जहाँ ९० प्रति शत से भी अधिक जन-संख्या अब भी कृषि में लगी है। फल-स्वरूप दोनों गाँवों के जीवन-स्तर में पर्याप्त विभेद पाया जाता है।

प्रति व्यक्ति वार्षिक आय हूँ बो हल्ली में २७४ रुपये है, जबकि चित्रपल्ली में २२४ रुपये। हूँ बो हल्ली में विकास की शक्तियों की जो हवा बही उसका पास के गाँव की अर्थ-व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका एक ही कारण है कि हूँ बो हल्ली में गैर-खेतिहर विभाग का विकास हाल ही में हुआ है और वह भी आकस्मिक रूप से। सर्वेक्षण से करीब छ वर्ष पूर्व हूँ बो हल्ली भी चित्रपल्ली के समान ही अविकसित था। एक पुनर-स्थापन योजना के अन्तर्गत हूँ बो हल्ली में कई परिवार आकर बसे। इनके साथ हूँ बो हल्ली में न केवल व्यावसायिक चातुर्य आया बल्कि कई आत्म निर्भर गैर-खेतिहर प्रतिष्ठानों की स्थापना भी हुई। इससे हूँ बो हल्ली की अर्थ-व्यवस्था को एक झकझौला लगा, लेकिन उसका चित्रपल्ली पर कोई तुरन्त प्रभाव नहीं पड़ा।

काम-धंधों का सम्मिश्रण

गाँवों में बहुत कम परिवार एक ही पेशे में लगे हैं, क्योंकि या तो परिवार के सभी व्यक्तियों के लिए एक ही पेशे में, खास कर गैर-खेतिहर धंधे में, काम प्राप्त करना मुश्किल है या फिर हो सकता है कि परिवार के सभी कमाऊ व्यक्तियों के लिए अपने को एक ही पेशे तक सीमित रखना लाभप्रद न हो, जैसे कृषि में। उक्त दो गाँवों में विभिन्न प्रकार के काम-धंधों में लगे व्यक्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि हूँ बो हल्ली में

परिवार के ७९ प्रति शत पुरुष और ७० प्रति शत महिलाएँ परिवार के मुख्य पेशे में लगी हैं। चित्रपल्ली के लिए इनका प्रातिशत्य क्रमशः ६७ और ६० है। इन दो गाँवों के काम-धंधों के सम्मिश्रण के सम्बन्ध में एक बात यह मिलती है कि पूरक अथवा सहायक और स्वतंत्र काम-धंधों में लगे व्यक्तियों का अनुपात हूँ बो हल्ली में चित्रपल्ली की अपेक्षा काफी अधिक है। उदाहरण के लिए सहायक धंधों में लगे व्यक्तियों का अनुपात हूँ बो हल्ली में ६३ प्रति शत और चित्रपल्ली में ४८ प्रति शत है। इसके अतिरिक्त किसी ने यह नहीं बताया कि चित्रपल्ली में कोई स्वतंत्र काम है, जबकि हूँ बो हल्ली में स्वतंत्र काम करनेवाले पुरुषों की संख्या करीब दो प्रति शत और प्रौढ महिलाओं की ०.३ प्रति शत है।

कुल मिला कर हूँ बो हल्ली में ८५ प्रति शत और चित्रपल्ली में ७१ प्रति शत कार्यकारी प्रौढ पुरुष केवल एक ही काम करते हैं—या तो वे मुख्य पेशे में लगे हैं अथवा फिर पूरक में—तथा शेष व्यक्ति एक में अधिक कामों में लगे हैं, जिनका संयोग इस प्रकार है 'मुख्य और सहायक', 'मुख्य तथा स्वतंत्र' आदि। ऐसा बताया गया कि हूँ बो हल्ली में २१ प्रति शत और चित्रपल्ली में ३२ प्रति शत प्रौढ महिलाएँ दो धंधों में लगी हैं। लेकिन महिलाओं के मामले में सम्मिश्रण प्रायः परिपूर्ण रूप से 'मुख्य और सहायक' का है। समग्र गाँव को एक साथ लेकर विचार करने पर पता चलता है कि हूँ बो हल्ली में ९५ प्रति शत प्रौढ पुरुष और ५७ प्रति शत प्रौढ महिलाएँ उत्पादक कार्यों में लगी हैं, जबकि चित्रपल्ली में प्रौढ पुरुषों और महिलाओं का तत्सम्बन्धी अनुपात क्रमशः ९६ तथा ६५ प्रति शत है। इसके अलावा दोनों ही गाँवों में अप्रौढों से भी काम लिया जाता है। हूँ बो हल्ली में कुल अप्रौढ पुरुषों का ३५ प्रति शत और महिलाओं का १० प्रति शत काम करता है। चित्रपल्ली में यह प्रातिशत्य क्रमशः २० और १८ है। तथापि, अप्रौढ पुरुष व महिलाएँ सभी परिवार के मुख्य पेशे में काम करती हैं।

अब यह एक सामान्य धारणा है कि एक अल्प विकसित देश की विकास-प्रक्रिया का प्रतिबिम्ब इस बात में मिलता

है कि लोगो ने प्राथमिक विभाग से मध्यम तथा गौण यानी तृतीय श्रेणीवाले विभाग को कितना अपनाया है। इसलिए इस परिवर्तन के परिमाण कोामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास का द्योतक माना जा सकता है। इस दृष्टि से परिवारों के वर्तमान और भूतकालीन प्रधानों के मुख्य पेशों के सम्बन्ध में आकड़े इकट्ठे किये गये तथा पिता के बाद पुत्र द्वारा विभिन्न विभाग अपनाने सम्बन्धी परिमाण का हिसाब लगाया गया।

तालिका २

पिता के बाद पुत्र द्वारा पेशा-परिवर्तन का प्रातिशत्य

विभाग	ह बो हल्ली	चित्रपल्ली
प्राथमिक	- ३७४	- २६
माध्यमिक	+ ६१५	+ १४३
तृतीयक	+ ७५२	+ १८०

तालिका २ उक्त दोनों गाँवों में एक पीढ़ी के दौरान काम-धंधों में आये परिवर्तन के आकड़े दर्शाती है। तुलनात्मक रूप से पिता के बाद पुत्र द्वारा पेशा परिवर्तन ह बो हल्ली में अधिक मिलता है। प्राथमिक विभाग में ह बो हल्ली में पर्याप्त गिरावट आयी। वहाँ यह गिरावट ३७ प्रति शत रही, जबकि चित्रपल्ली में तीन प्रति शत।

ह बो हल्ली में जिन लोगो ने खेती का काम छोड़ा उन्होंने प्रशोधन व उत्पादन, परिवहन तथा शैक्षणिक एवम् क्लर्की के काम में रोजगार प्राप्त किया। इस प्रकार ह बो हल्ली में माध्यमिक श्रेणी के काम-धंधों में ६२ प्रति शत और तृतीयक श्रेणीवाले कामों में ७५ प्रति शत वृद्धि हुई।

पेशों में परिवर्तन का प्रभाव तालिका ३ में और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें दो पीढ़ियों के दौरान विभिन्न प्रकार के काम-धंधों में लगे लोगो का अनुपात प्रस्तुत किया गया है।

निम्न आकड़ों से यह समझा जा सकता है कि जहाँ एक ही पीढ़ी में ह बो हल्ली में कृषि पर निर्भर रहनेवाले व्यक्तियों का प्रातिशत्य ६४ से गिर कर ४० हो गया, वहाँ चित्रपल्ली में कोई खास परिवर्तन नहीं

आया। ह बो हल्ली में जो व्यक्ति खेती से मुक्त हुए उन्होंने भूगफली के कारखानों, होटलों तथा अन्य छोटे प्रतिष्ठानों में काम प्राप्त किया। यह बात स तथ्य

तालिका ३

दो पीढ़ियों के वक्त विभिन्न काम-धंधों में लगे व्यक्तियों का प्रातिशत्य

पेशा	ह बो हल्ली चित्रपल्ली			
	परिवार का प्रधान			
	पिता	पुत्र	पिता	पुत्र
प्राथमिक उत्पादन	६३५	४०१	९३४	९११
खाद्यान्न प्रशोधन, वस्त्रोत्पादन आदि	१४१	२५५	३८	३१
वाणिज्य	७६	९२	०३	२८
परिवहन	१०	२६	—	—
निर्माण व अन्य उपयोगी कार्य	५०	६३	१०	१०
स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम-प्रशासन आदि	२४	५४	०३	०३
अन्य सेवाएँ	४०	१०१	०३	१७
अनुत्पादक	२४	०७	०९	—
योग	१०००	१०००	१०००	१०००

में प्रतिबिम्बित होती है कि अब प्रशोधन, उत्पादन और वाणिज्य सम्बन्धी गैर-खेतिहर कामों पर निर्भर रहनेवाले व्यक्तियों का प्रातिशत्य एक पीढ़ी पहले के व्यक्तियों से अधिक है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि उक्त दोनों गाँव एक-दूसरे के बहुत निकट हैं, तथापि किसी खास गैर-खेतिहर काम-धंधे के अभाव में चित्रपल्ली में पेशों सम्बन्धी परिवर्तन बहुत कम हुआ है। इसके विपरीत ह बो हल्ली के काम-धंधे के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन आया है। ह बो हल्ली बढ़ते हुए गैर-खेतिहर विभाग के साथ बड़ी द्रुत गति से एक कस्बे के समान रूप ले रहा है। आशा की जा सकती है कि पड़ोसी चित्रपल्ली गाँव भी शीघ्र ही इस प्रवाह में आ जायेगा।

शिमोगा (मैसूर) १९ नवम्बर १९६३

पंचायत राज और सामुदायिक विकास

नफीस बेग

यदि सामुदायिक विकास के लिए प्रवर्तक शक्ति जनता की ओर से आनी है, तो योजना बनाने और कार्यान्वित करने में लोक-भागीदारी का होना एक परमावश्यकता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (पंचायत राज) का उद्देश्य है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए लोक-अभिक्रम जगाना और उनका समर्थन प्राप्त करना।

‘सामुदायिक विकास’ अपेक्षाकृत नया शब्द है। राष्ट्र सघ के अनुसार ‘सामुदायिक विकास’ का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके जरिये समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थाएँ सुधारने, इन समुदायों को राष्ट्रीय जीवन में मिलाने तथा राष्ट्रीय प्रगति में इन्हें पूर्ण योगदान देने योग्य बनाने के लिए जनता द्वारा किये गये प्रयासों को सरकारी अधिकारियों के प्रयासों से संयुक्त किया जाता है। हम भारतवासियों के लिए ‘समुदाय’ अथवा ‘समाज’ का अलग ही अर्थ है, इसका उपयोग ‘हिन्दू समाज,’ ‘मुस्लिम समाज’ अथवा ‘ब्राह्मण’ या ‘सीया’ समाज के रूप में किया जाता है। फिर, ‘व्यापारी समाज’ भी प्रचलित है। विदेशी शासन-काल में हमारे यहाँ ‘सामुदायिक विकास’ करके कुछ नहीं था। बेशक कई कार्यक्रम तब भी चलते थे, जोकि सचमुच ही सामुदायिक विकास के ही विभिन्न पहलू थे। जैसे, ग्राम विकास, ग्रामोन्नति, प्रौढ शिक्षा आदि की योजनाएँ। लेकिन विकास के लिए कोई समन्वित प्रयास नहीं किया जाता था और कोई खास परिणाम भी नहीं निकला। आजादी मिलने और सामुदायिक विकास आन्दोलन शुरू होने के बाद ‘सामुदायिक विकास’ शब्द का अर्थ हुआ वार्षिक, जातीय, सामाजिक और आर्थिक भेद को अलग रखते हुए ग्राम समाज के हर पहलू को छूनेवाले समग्र कार्यक्रमों का विस्तृत विचार।

करीब ग्यारह साल पहले अक्टूबर १९५२ में ‘सामुदायिक विकास’ कार्यक्रम भारत में योजित विकास प्रक्रमों के अग स्वरूप आरम्भ किया गया। देश के अन्य भागों

में इसका तेजी में विस्तार किया गया और चन्द वर्षों में इसके अन्तर्गत देश की करीब ७० प्रति शत ग्रामीण आबादी आ गयी, सन् १९६३ के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण भारत को लाने की योजना है। यह कार्यक्रम शैक्षणिक भी है और सगठनात्मक भी, इसका उद्देश्य है ग्रामीणों में उन्नत जीवन के लिए लालसा पैदा करना और मुख्यतः स्वयं-सेवा के जरिये ही इसकी पूर्ति के लिए राह दिखाना। इस उद्देश्य की पूर्ति, जब कभी आवश्यक हो, वर्तमान ग्रामीण संस्थाओं को प्राणवान बना कर तथा नयी संस्थाएँ खड़ी करके करनी है। ग्राम समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पहले जो प्रयास किये गये, उनसे यह अनुभव हुआ कि लोगों का जीवन-स्तर उन्नत करने के लिए जीवन के हर पहलू का—कृषि, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि—समावेश करनेवाला सघन और विस्तृत कार्यक्रम परमावश्यक है, और इस कार्यक्रम को एक संयुक्त माध्यम के जरिये फैलाना चाहिए। यद्यपि यह जन-सहयोग के साथ सरकारी कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ, मूल नीति इसे जन कार्यक्रम में बदलने की थी, सरकारी सहयोग सिर्फ प्रोत्साहन हेतु ही रहता।

जन-सहयोग

भारत में जिस मूल उद्देश्य पर ‘सामुदायिक विकास’ आधारित है, वह यह है कि इसे आगे बढ़ाने में मुख्य शक्ति जनता की लगनी चाहिए। उद्देश्य इसे सचमुच ही जन-आन्दोलन बनाने का है। अतः गाँव के सामाजिक और आर्थिक जीवन का परिवर्तन करने में इस उद्देश्य

की कहीं तक पूर्ति हो रही है, जन-सहयोग इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। हम यो भी कह सकते हैं कि गाँवों का चित्र मुख्यतः हर व्यक्ति द्वारा विकास कार्यक्रम में भाग लेने पर निर्भर करता है। सर्वोत्तम ढंग से इसकी पूर्ति लोगों द्वारा अपनी पंचायत और अन्य ग्राम समितियों जैसी प्रतिनिधि सस्थाओं के जरिये कार्य का संगठन करके ही की जा सकती है। सच तो यह है कि कल्पनानुसार सामुदायिक विकास की एक विशिष्टता है लोकतांत्रिक आयोजन और कार्यान्वयन पर बल। इसमें नीचे से निर्माण की योजना बनानी होती है और उसके आयोजन तथा कार्यान्वयन में जनता का हाथ होता है। इसे दोहराने की जरूरत नहीं है कि यदि पंचायत राज सस्थाओं के जरिये इसका कार्यान्वयन किया जाय तो यह ग्रामीणों को विकास और अपने तथा पूरे लोकतंत्र में भी अपने स्थान का महत्व समझने योग्य बना कर लोकतंत्र की नींव मजबूत करेगा।

भारत ने लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्थिक सस्थाओं और प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण का रास्ता खोजना है। इस दिशा में 'पंचायत राज' की स्थापना कर 'सहयोगी लोकतंत्र' की नींव डाल दी गयी है। यह ज्ञात होना चाहिए कि पंचायत राज के लिए पहल मूलतः लोकतंत्र के आधार को विस्तृत करने के राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की चिन्ता से आयी। पंचायत राज के जरिये विकास की यह योजना प्रगति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके पीछे विचार यह है कि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अन्ततः अधिकाधिक ग्राम और खंड के लोगों पर रहेगी।

मेहता समिति की रिपोर्ट

योजना परियोजना समिति ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए जो अध्ययन दल नियुक्त किया था, लोकतांत्रिक सस्थाओं अथवा 'पंचायत राज' के जरिये 'सामुदायिक विकास'

की योजना उसी की सिफारिशों का परिणाम है। अध्ययन दल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आरम्भ के समय से इसके कार्यान्वयन की जाँच की और यह बताया कि जब तक विकास की जिम्मेदारी खंड स्तर पर किसी लोकतांत्रिक सस्था को नहीं दी जाती, विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जनता में पहल लाने तथा ग्राम के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए ग्राम समाज को जिम्मेदार बनाने के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। दल का मत था कि जिले के अन्दर योजना बनाने के लिए सबसे सहज इकाई है सामुदायिक विकास खंड। दल ने एक योजना बनायी जिसमें त्रि-सूत्री संगठन की कल्पना थी। हर स्तर का पूरे संगठन में प्राणवान सम्बन्ध है, जैसे ग्राम स्तर पर पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का।

इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अथवा पंचायत राज की योजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में बलवन्त राय समिति की सिफारिशों को १९५८ से स्वीकार किये जाने का सामुदायिक विकास कार्यक्रम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एक व्यापक पद्धति के अन्तर्गत विकास योजनाओं के आयोजन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में पहल और जिम्मेदारियों के स्थानान्तरण से लोगों का बड़े पैमाने पर सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस तरह के परिवर्तन से लोगों के मन में यह भाव पैदा होगा कि गाँव का जीवन बदलना गाँववालों के हाथ में है। बेशक सरकार से आवश्यक सहायता मिलेगी, परन्तु मूलतः जनता की नीति और कार्यवाही ही परिवर्तन के स्वरूप को निश्चित करेगी। गाँवों की आर्थिक जीव्यता पर आवारित प्रत्येक गाँव अथवा ग्राम समूह के लिए एक ग्राम पंचायत रहेगी, जोकि प्राथमिक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने और सामुदायिक विकास तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। सम्पूर्ण विकास खंड के लिए पंचायत समिति वह मुख्य सस्था है जोकि खंड विकास की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। कुछ

राज्यों में समितियों के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, कुछ न ग्राम पंचायतों के सरपंच स्वयंसेवक इनके सदस्य बन जाते हैं। इनमें महिलाओं, परिगणित जातियों और सहकार आन्दोलन में सम्बन्धित लोगों आदि के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान है, जिनके प्रतिनिधियों को समितियों के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है। इसके ऊपर रहेगी जिला परिषद, जिसके सदस्य जिलाधीश, जिला अधिकारीगण, जिले के विधायकगण और मसद-सदस्य तथा पंचायत समितियों के प्रमुख रहेंगे। पंचायत राज का उद्देश्य है कार्यक्रम का कार्यान्वयन जनता और उसके प्रतिनिधियों के जरिये करवाना। परिवर्तित अवस्था में खड के कर्मियों को पेशेवर नेता, आयोजक, प्रौढ शिक्षक आदि के रूप में अधिकाधिक सख्या में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जायगा।

पंचायत राज अथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सहकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण देने हेतु बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करने की क्षमता है। हम यह याद रखना चाहिए कि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया था तब लोगों में कितना बड़ा उत्साह था। हमें वही उत्साह फिर से पैदा करना है, परन्तु जरा बड़े पैमाने पर। उत्पादक कार्यों के लिए यह उत्साह पैदा करने हेतु सावधानीपूर्वक तथा समय पर कार्यवाही की जानी चाहिए। पंचायत राज की सफलता के लिए यह अत्यावश्यक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी और प्रशासनिक स्वरूप की समग्रता तथा उन्हें दी गयी जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता बनाये रखनी ही चाहिए, जबकि उनका ज्ञान और अनुभव जिला तथा खड स्तरीय निर्वाचित सस्थाओं को उपलब्ध किया जाय।

अब तक प्राप्त सीमित अनुभव के आधार पर सामुदायिक विकास के क्षेत्र में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रभावशाली और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्न सुझाव दिये जाते हैं

१ पंचायतो और पंचायत समितियों को सहयोगियों के पूर्ण सहयोग से समाज के गरीबतर वर्गों की आवश्यक-

ताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री और सेवाओं का समय तथा समय पर वितरण हो। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री का इस्तेमाल उम्मी में किया जाय, जिस हेतु वह दी गयी है।

२ पंचायत समिति कोष का कुछ हिस्सा कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास और कल्याण हेतु विशिष्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए अलग कर देना चाहिए।

३ ऐच्छिक सस्थाओं को यथा सम्भव पंचायत समितियों के सहयोग से कार्य करना चाहिए। उन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए दी जानेवाली निधि राज्य सरकार, परिषदों और पंचायत समितियों के जरिये दी जाय।

४ केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय को योजना आयोग और अखिल भारत ऐच्छिक सस्थाओं के परामर्श में इस बात का अध्ययन और निश्चय करना चाहिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हेतु पंचायत राज सस्थाओं के लिए उन सस्थाओं का कितना सर्वोत्तम सहयोग और सहायता प्राप्त की जा सकती है।

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रशामन को जनता के निकट सम्पर्क में लायेगी और इस प्रकार योग्यता भी बहुत बढ़नी चाहिए। पंचायत राज योजना के मूल सिद्धान्तों से तो किसी को कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। स्वायत्त शासन हमारे देश के लिए कोई नयी वस्तु नहीं है और यद्यपि विदेशी शासन-काल में इसने बहुत ऊँच-नीच देखे हैं, पंचायतो की भव्य-क्षमता सर्वमान्य है। हमारे संविधान में कहा गया है— “सरकार ग्राम पंचायतों के संगठन बनायेगी और उन्हें ऐसे अधिकार देगी जोकि उन्हें स्वायत्त सरकार की इकाइयाँ बनाने के लिए आवश्यक होंगे।” प्रथम पंच वर्षीय योजना में यह बताया गया था कि पंचायतो को ग्राम निर्माण और विकास का माध्यम होना चाहिए। जब तक गाँव की सस्था गाँव के साधन-स्रोतों का विकास करने के लिए जिम्मेदारी लेने और पहल करने की अवस्था में नहीं होती, ग्रामीण जीवन पर कोई विशेष प्रभाव डालना कठिन होगा, क्योंकि ग्राम पंचायतो और ग्राम सहकारी समितियों जैसी ग्रामीण सस्थाएँ ही आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकेगी। यही ‘सामुदायिक विकास’ आन्दोलन का मार्ग है।

खादी-ग्रामोद्योग तथा उनकी स्फीति निवारक क्षमता

सोमनाथन नायर

एक विकासोन्मुख देश में मुद्रा-स्फीति को रोकने और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान आय का प्रसार करने अर्थात् इन दोनों ही दृष्टियों से उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन अपरिहार्य है। प्रस्तुत लेख में इस बात का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है कि खादी और ग्रामोद्योगों ने इस दिशा में कितना योगदान दिया है।

रोजगारी के आधुनिक सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण तत्व गुणक है। यह विनियोजन में प्रारम्भिक अभिवृद्धि तथा सम्पूर्ण आय में अन्तिम अभिवृद्धि के बीच का सम्बन्ध प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह विनियोजन में परिवर्तन के प्रति आय में परिवर्तन का अनुपात है। विनियोजन का उद्देश्य सिर्फ मूल विनियोजन की राशि के अनुपात से ही आय बढ़ाना नहीं होता, बल्कि मूल विनियोजन के अनुपात से भी अधिक आय करना होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मूल विनियोजन सिर्फ उन्हीं उद्योगों की आय में अभिवृद्धि नहीं करता, जिनमें वह किया जाता है, बल्कि उन अन्य उद्योगों की आमदनी को भी बढ़ाता है जिनके उत्पादनों की आवश्यकता विनियोजित उद्योगों में पड़ती है। गुणक की मात्रा उपभोग करने की सीमान्त प्रवणता की मात्रा पर निर्भर करती है। उपभोग करने की सीमान्त प्रवणता की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, गुणक का आकार भी उतना ही बड़ा होगा और इसी प्रकार गुणक की मात्रा जितनी ही अधिक होगी उपभोग करने की सीमान्त प्रवणता भी उतनी ही अधिक होगी।

विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्थाओं में

गुणक का सिद्धान्त विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्थाओं में भी काम करता है किन्तु उसका आकार सिर्फ उपभोग करने की सीमान्त प्रवणता पर ही नहीं बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आय रूपी स्रोत से रिसाव कितना होता है। आय स्रोत से होनवाले सामान्य रिसाव

इस प्रकार हैं (१) ऋण-अदायगी यानी आय की नयी अभिवृद्धि के एक अंश को पुराना ऋण चुकाने के काम में लाना। इस प्रकार उपभोग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, (२) रकम का बन्द पड़ जाना यानी बढी हुई आय का एक अंश बचा कर निष्क्रिय रूप में रखा जा सकता है, जिसका उपभोग वृद्धि पर असर नहीं पड़ सकता, (३) पुराने शेयरों एवं सेक्यूरिटियों की खरीद यानी नयी आय का एक अंश दूसरों से पुराने शेयर तथा सेक्यूरिटियों की खरीद के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और उनकी बिक्री से हुई प्राप्ति का उपभोग में इस्तेमाल नहीं होता, (४) आयात यानी आयातीत माल पर व्यय की जानेवाली राशि का देशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ाने पर विशेष असर नहीं पड़ेगा, किन्तु उसे घरेलू आय के स्रोत से एक महत्वपूर्ण रिसाव समझा जा सकता है, और (५) मूल्य-स्फीति यानी मूल्य-स्फीति के कारण बढी हुई आय का एक बहुत बड़ा अंश उपभोग, आय और रोजगारी बढ़ाने की बजाय उच्चतर मूल्यों को अदा करने में ही व्यय हो जायेगा। इन रिसावों के कारण अग्र वृद्धि की प्रक्रिया शीघ्र ही खत्म हो जा सकती है। आय के स्रोत से ये रिसाव जिस हद तक बन्द किये जा सकेंगे, विनियोजन की प्रारम्भिक वृद्धि का आय-सृजन में उतना ही अधिक गुणक प्रभाव पड़ेगा।

उपभोक्ता सामग्री

फिर भी, यह आवश्यक नहीं है कि प्रारम्भिक विनियोजन पूँजीगत वस्तुओं या सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए परिव्यय हो। वह उपभोक्ता वस्तुओं

के उत्पादन के लिए भी हो सकता है। प्रारम्भिक व्यय का स्वरूप जो भी हो-चाहे वह विनियोजन पर हो या उपभोग पर-हेन्सेन* के शब्दों में उसका असर जहाँ तक गुणक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, एक-सा ही पड़ना है।

आय प्रसार की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण शर्त है-उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि। अगर उपभोक्ता वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो गुणक का काम होता रहेगा और नयी आय का प्रसार बढ़ता जायेगा। भारत जैसे विकसित देश में सीमान्त उपभोग प्रवणता की कमियों के कारण गुणक के काम की सीमा निर्धारित नहीं होती। दर असल, ऐसे देश में सीमान्त उपभोग प्रवणता तो बहुत अधिक होती है। मनुष्य अधिक महत्वपूर्ण पहलू तो उपभोग वस्तुओं की उपलब्धि है।

२

विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में नये विनियोजन का एक दूसरा पहलू भी है। विकसित देशों में औद्योगिक उत्पादनो में लचकदार पूर्ति रेखा (शीघ्र पूर्ति) की तुलना में अल्प विकसित या कृषि-प्रधान देशों में खाद्य के मामले में गैर लचकदार पूर्ति रेखा (शिथिल पूर्ति नहीं) की वजह से विनियोजन तथा उत्पादन की अभिवृद्धि के बीच विलम्ब आ जाता है, जिसके परिणाम-स्वरूप विस्तार की प्रक्रियाओं में रुपये-पैसे की गन्दावली में आय और वस्तुओं के मूल्य वास्तविक आय और उत्पादन से अधिक तेज रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, विनियोजन और उत्पादन की इस बीच की अवधि में वस्तुओं की पूर्ति उनकी माँग को पूरा कर सकने में असमर्थ रहेगी और तब मुद्रा-स्फीति की स्थिति आ सकती है। इस प्रकार कम से कम अस्थायी तौर पर ही अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि आ जायेगी। विकास के लिए विनियोजन के तत्व का तथा उसके परिणाम-

स्वरूप रुपये-पैसे की पूर्ति और उधार विस्तार के सदर्थ में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों की प्रवृत्ति का विश्लेषण उद्युक्त दृष्टिकोण का प्रमाण है।

राष्ट्रीय आय

सही अर्थों में प्रथम और द्वितीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय या उत्पादन स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर क्रमशः ३४ और ४१ प्रति शत वार्षिक की दर से बढ़ा है। (देखिए तालिका १।) रकम के रूप में यानी प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रथम और द्वितीय योजना-काल में क्रमशः १०८ और ७३४ प्रति शत के हिसाब से वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में सही अर्थों में, प्रचलित मूल्यों के आधार पर आय में जो सालाना वृद्धि हुई उससे २३२ प्रति शत अधिक वृद्धि हुई और इसकी वजह से मूल्यों पर दबाव नहीं पड़ा। पर दूसरी योजना की अवधि में प्रचलित मूल्यों के आधार पर आय में सालाना वृद्धि वास्तविक आय से ३२४ प्रति शत अधिक हुई। इस प्रकार दूसरी योजना की अवधि में मूल्यों में लगभग ३२४ प्रति शत सालाना वृद्धि हुई।

उत्पादन

कृषि उत्पादन का सूचकांक १९५५-५६ के ११६३ प्रति शत से बढ़ कर १९६०-६१ में १३९९ प्रति शत हो गया (आधार १९५०=१००)। सन् १९६१-६२ में उत्पादन उन्नीस स्तर पर रहा। औद्योगिक उत्पादन १९५७ के १०४१ प्रति शत से बढ़ कर १९६१ में १३९३ प्रति शत तक पहुँच गया (आधार १९५६=१००)। अस्थायी आकड़ों से पता चलता है कि १९६२ में सूचकांक १४९५ तक बढ़ा। सन् १९६२ की यह वृद्धि दूसरी योजना की अवधि में वृद्धि की औसत दर से अस्थायी तौर पर ही ऊँची रही। इस प्रकार वास्तविक राष्ट्रीय

* हेन्सेन : ए गाइड टू कीन्स, मैकमिलन बुक कम्पनी, न्यूयार्क; १९५२; पृष्ठ ९०।

§ रिपोर्ट ऑन करेंसी एण्ड फायनेंस फॉर १९६२-६३,

तालिका १

राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में झुकाव

वर्ष	१९४८-४९ के मूल्यो के आधार पर राष्ट्रीय आय (करोड रुपयो मे)	प्रचलित मूल्यो के आधार पर राष्ट्रीय आय (करोड रुपयो मे)	१९४८-४९ के मूल्यो के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (रुपयो मे)	प्रचलित मूल्यो के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (रुपयो मे)
१९५१-५२	९,१०० (+२८)	९,९७० (+४६)	२५०३ (+११)	२७४२ (+२९)
१९५२-५३	९,४६० (+४०)	९,८२० (-१५)	२५५७ (+२२)	२६५४ (-३२)
१९५३-५४	१०,०३० (+६०)	१०,४८० (+६७)	२६६२ (+४१)	२७८१ (+४८)
१९५४-५५	१०,२०८ (+२५)	९,६१० (-८३)	२६७८ (+०६)	२५०३ (-१००)
१९५५-५६	१०,४०८ (+१९)	९,९०८ (+३९)	२६७८ (-)	२५५० (+१९)
१९५६-५७	११,००० (+५०)	१,३१० (+१३३)	२७५६ (+२९)	२८३३ (+१११)
१९५७-५८	१०,८०९ (-१०)	११,३९० (+०७)	२६७३ (-३०)	२७९६ (-१३)
१९५८-५९	११,६५० (+७०)	१२,६०० (+१०६)	२८०१ (+४८)	३०३० (+८४)
१९५९-६०	११,८६० (+१८)	१२,९५० (+२८)	२७९२ (-०३)	३०४८ (+०६)
१९६०-६१*	१२,७५० (+७५)	१४,१६० (+९३)	२९३७ (+५२)	३२६२ (+७०)
१९६१-६२†	१३,०२० (+२१)	१४,६३० (+३३)	२९३४ (-०१)	३२९७ (+११)

टिप्पणी कोष्ठक के आकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में प्रातिशत्य विभेद (जोड़ और घटाव) बताते हैं । इसी प्रातिशत्य के आधार पर प्रथम और द्वितीय योजनाओं की अवधि में वार्षिक विभेद का अंदाज लगाया गया है ।

*सशोधित ।

†प्रारम्भिक ।

स्रोत रिपोर्ट ऑन करेमी एण्ड फायनेस फॉर १९६२-६३, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई; पृष्ठ : २२ ।

उत्पादन में निरपेक्ष झुकाव के साथ अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक स्वरूप में मामूली परिवर्तन ही हुआ है । §

मूल्य

सन् १९५५-५६ और १९६२-६३ के बीच उपभोग

§ इकनॉमिक सर्वे ऑफ एशिया एण्ड दि फार ईस्ट,

१९६१, राष्ट्र संघ, बैंकाक; १९६२, पृष्ठ ८२ ।

की समस्त वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक ३५४ प्रति शत बढ़ा (आधार १९५२-५३=१००) । उसी आधार पर उसी अवधि में कृषिक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक ३५३ प्रति शत तथा अकेले खाद्य पदार्थों का ३९५ प्रति शत बढ़ा । उसी आधार पर, उसी अवधि में औद्योगिक कच्चे माल तथा निर्माण सामग्री के

थोक मूल्य सूचकांक क्रमशः ३७५ प्रति शत तथा २९.० हैं, क्योंकि अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन और आय की प्रति शत ऊपर उठे। इनका तथा साथ ही साथ दरों में वृद्धि में अधिक मूल्यों में वृद्धि हुई है। विश्लेषण

तालिका २

थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार १९५२-५३)

वर्ष	सभी वस्तुएँ	कृषिक वस्तुएँ	खाद्य वस्तुएँ	औद्योगिक कच्चा माल	निर्माण सामग्री	शराब व तम्बाकू	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व स्नेहक द्रव्य
१९५१-५२	११८०	११८८	१११०	१४१५	११९३	१२१९	९६५
१९५५-५६	९२५	८८०	८६६	९००	९९७	८१०	९५२
१९५६-५७	१०५३	१०८५	१०२३	११६०	१०६३	८४४	१०४२
१९५७-५८	१०८८	१०७४	१०६४	११६५	१०८१	९४०	११३५
१९५८-५९	११२९	११८०	११५०	११५६	१०८४	९५४	११५४
१९५९-६०	११७१	११६५	११९०	१२३७	१११७	९९५	११६५
१९६०-६१	१२४९	१२३८	१२००	१४५४	१२३९	१०९९	१२००
१९६१-६२	१२५१	१२२८	१२०१	१४२६	१२६६	१००३	१२२१
१९६२-६३	१२७९	१२३३	१२६१	१३६५	१२८९	१०००	१२४३

स्रोत 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन', जून १९६३, पृष्ठ - ८७७।

शराब, तम्बाकू, ईंधन, शक्ति तथा स्नेहक द्रव्यों सबन्धी वित्त वितरण तालिका २ में दिया गया है।

जीवन-यापन का खर्च

जीवन-यापन के सूचकांक में मोटे तौर पर थोक मूल्य के अनुरूप ही हेरफेर हुआ है। सन् १९५५-५६ से (आधार १९४९=१००) मजदूर वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३५ प्रति शत बढ़ा है। मध्यम वर्ग का जीवन-यापन सूचकांक १९५५ के ३९३ बिन्दु से बढ़ कर १९६० में ४५३ बिन्दु तक पहुँच गया। (आधार १९३९=१००)। इसका विस्तृत विवरण तालिका ३ में दिया गया है।

उक्त अनुच्छेदों से स्पष्ट रूपेण असतुलन प्रकट होता

से यह भी प्रकट होता है कि प्रथम योजना-काल के अंत में अर्थ-व्यवस्था में सतुलन की स्थिति थी, मुद्रा-सम्भरण और उत्पादन कम-वेश बराबर अनुपात से बढ़े। इस प्रकार प्रथम योजना-काल में मुद्रा-स्फीति का व्यवहारगत कोई दबाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ। किन्तु दूसरी योजना की अवधि में यह स्थिति उल्टी हो गयी।

स्फीत्यात्मक मुकाब

अनुक्रमिक पंच वर्षीय योजनाओं में विनियोजन बढ़ाने के परिणाम-स्वरूप मुद्रा-सम्भरण का विस्तार ११ अरब ५६ करोड़ ६० लाख रुपये तक पहुँच गया है यानी मई १९६३ के अन्त में समाप्त होनेवाले आठ वर्षों में लगभग ५२ प्रति शत बढ़ा है। द्वितीय योजना

में ४६ अरब रुपये के योजना परिव्यय के समक्ष मुद्रा गतिविधियों से उन लोगो की क्रय-शक्ति और भी बढ़ेगी, संग्रहण तथा बैंक ऋण का विस्तार क्रमशः ५ अरब जिनकी सीमा उपभोग प्रवणता एक से अधिक है

तालिका ३

जीवन-यापन का सूचकांक

वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (श्रमजीवी वर्ग-आधार १९४९=१००)	जीवन-यापन सूचकांक (मध्यम वर्ग-आधार १९३९=१००)		
		सामान्य	खाद्य	वस्त्र
१९५५-५६	९६	३९३	४४२	४९७
१९५६-५७	१०७	४१२	४७०	५३०
१९५७-५८	११२	४२६	४८८	५४५
१९५८-५९	११८	४३८	५०७	५४९
१९५९-६०	१२३	४४६	५१३	५४९
१९६०-६१	१२४	४५३	५२५	५६९
१९६१-६२	१२७	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
१९६२-६३	१३१	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य

स्रोत (अ) रिपोर्ट ऑन करेन्सी एण्ड फायनेन्स फार १९६२-६३ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई,
(आ) कैपीटल, कलकत्ता।

२८ करोड़ ८० लाख रुपये तथा ३ अरब ८७ करोड़ ८० लाख रुपये तक हुआ। इसके साथ ही साथ दूसरी योजना की अवधि में ९ अरब ४८ करोड़*रुपये का हीनार्थ प्रवन्ध किया गया। इससे मूल्यों की वृद्धि तथा मुद्रा-सम्भरण के विस्तार के बीच तात्कालिक सम्बन्ध स्थापित हुआ, साथ ही साथ इससे यह भी प्रतीत होता है कि अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए विचार करने पर उत्पादकता की गति इतनी पर्याप्त नहीं रही कि मुद्रा-सम्भरण के विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। (देखिए तालिका ४।)

तीसरी पंच वर्षीय योजना के शुरु होने के समय से लेकर मुद्रा-सम्भरण तथा बैंक उधार का विस्तार क्रमशः १५ अरब २ करोड़ ८० लाख रुपये तथा २ अरब ९३ करोड़ २० लाख रुपये हुआ। इससे तथा योजनाओं के अंतर्गत विनियोजन कार्यक्रम के अनुसार बढ़ी हुई आर्थिक

और अधिकांश गुप्त उपभोक्ता माँग का दबाव आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ेगा।

प्रतिरक्षा व्यय

उपर्युक्त बातों में हाल में बढ़ा प्रतिरक्षा व्यय भी मिलाया जा सकता है। पिछले दो वर्षों में इस मद पर भारत का खर्च काफी बढ़ गया है। सन् १९६२-६३ के लिए सशोधित आकड़े ५ अरब ५ करोड़ रुपये के हैं। चालू साल के लिए प्रतिरक्षा परिव्यय ८ अरब ६७ करोड़ २३ लाख रुपये रखा गया है। (यह सभी को मालूम है कि प्रतिरक्षात्मक कार्यों में किया गया सारा व्यय आर्थिक शब्दावली में अनुत्पादक होता है।) अगर इसी अनुपात से वस्तुओं के, खास कर उपभोग की वस्तुओं के, उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई तो देश के इन सारे खर्चों का मूल्यों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा।

उपचार के तरीके

विकासोन्मुख देश में मूल्य वृद्धि की समस्याएँ विकसित

* तृतीय पंच वर्षीय योजना: १९६१ का अनुमान, पृष्ठ. ९९।

§ भारत सरकार का वर्ष १९६३-६४ के लिये बजट।

तालिका ५

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत अपभोक्ता सामग्री का उत्पादन : १९५५-६२

उद्योग	(मूल्य लाख रु में)				योग	
	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६१-६२ (१९५५-६२)
खादी	५५४३३	८२२५२	१,१४८३९	१,३७५७२	१,४१४४६	१,७५४५४ ८,४९३४५
ग्रामीण तेल	४१७०	९३६५	२६९२३	७८९९२*	१,२२८६४*	१,६६९१२* २,०७०३८* ६,१६२६४
ग्रामीण चर्म	८८	३५६	१०३८	१४४५	२६६२	३५५० ९१०८ १८२४७
कुटीर दिशासलाई	२१	७६	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य २५६*
गुड-खाण्डसारी	४८७८०	५०४९७	५७१३४	१,१९८६९	अप्राप्य	अप्राप्य २,७६२८०
ताड-गुड	४५५७०	३५६८९	अप्राप्य	अप्राप्य	२२९६९	२३०३९ ८९३१३
अखाद्य तेल और साबुन	२६७	६७३	१४६८	२०१९	३४७९	३६३७ १५०३५
हाथ कागज	१७६७	१६२५	१५६५	२११६	२३५८	२३९९ १४२५३
मुधुमक्खी-पालन	५७	१९८	५९७	१०६३	११८८	२२६० ७१०१
ग्रामीण कुम्हारी	कुछ नहीं	१११	३१९	१११३	१७५७	४१९८ १२४०६
रेखा	४०	४०	४८	४२४	१५५	६५६ १४१८ २७८१
कुल योग	१,५६१९३	१,८०८८२	२,०३९३१	३,४४६१३	२,७८२०५	३,२८७७३ ४,०८७८१ १९,०१३७८

अप्राप्य = मूल्य की शब्दावली में अनुपलब्ध । * तेल और खली सहित । † केवल नीरा के लिए, ताड़-गुड उत्पादन कमीशन के वार्षिक विवरण में मनों में दिया गया है ।
 ‡ उत्पन्न, दिस २६, १९६१ ग्रूस दियासलाई का विक्री मूल्य । अन्य वर्षों के लिए उत्पादन वार्षिक विवरण में ग्रूस की सख्या में ही दिया गया है, उनकी कीमत का उल्लेख नहीं है ।

स्रोत - खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के वार्षिक विवरण ।

देशों की समस्याओं से अलग होनी है और इसलिए उनके उपचार सम्बन्धी उपाय भी भिन्न होते हैं। विकसित देशों में मुद्रा-स्फीति को बड़ी आसानी से मोनेट्री तथा अर्थ-विषयक उपायों में एवम् वास्तविक वास्तव्य प्रतिवधों से रोका जा सकता है, क्योंकि उन देशों की अर्थ-व्यवस्था लगभग पूर्ण रोजगारी प्राप्ति की अवस्था में होती है और उनकी समस्याएँ उसे विकसित करने की नहीं, बल्कि विकास की स्थिति को बनाये रखने की होती है। इसके दूसरी ओर विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में इस तरह के उपायों का या तो कोई असर नहीं पड़ेगा या विकास के लक्ष्य तक पहुँचने में हानिप्रद होगा। ऐसी अवस्था में विकासोन्मुख देश में उपर्युक्त तरह के नकारात्मक उपायों के बदले उत्पादन बढ़ाने की सकारात्मक नीति अपनानी चाहिए। और, यहाँ भी इस बात का खयाल रखना चाहिए कि उपभोग की वस्तुओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मूल्यों पर उनका तत्काल और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

और इस सबके बावजूद, विकास की अवस्था में उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति एवम् उनकी माँग के बीच का फर्क जब तक दूर नहीं किया जाता, तब तक जन-संख्या और प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों पर गुणक प्रभाव लायेगी और परिणाम-स्वरूप मूल्यों में सर्वतोमुखी वृद्धि को आमंत्रण मिलेगा। अतः उपभोग की वस्तुओं के क्षेत्र में यथा सम्भव तीव्र गति से उत्पादन बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई बेहतर उपाय नहीं है।

३

यहाँ सरसरी तौर पर एक ऐसे अभिकरण की कार्य-शीलता का उदाहरण दिया जा सकता है जो सिर्फ उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में ही सलग्न है। इस कथन का तात्पर्य खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्य से है। इस लेख के दूसरे प्रकरण के सन्दर्भ में यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के बाद के उत्पादन का ही हवाला दिया गया है।

कमीशन के दायरे में आनेवाले १४ उद्योगों में से खादी तथा दस ग्रामोद्योगों का उत्पादन-१९५५-५६ से १९६१-६२ तक-कमीशन के प्रतिवेदनों के अनुसार, जिनमें कुछ उद्योगों का उत्पादन-मूल्य दिया गया है, लगभग दो अरब रुपये की कीमत का हुआ है। लेकिन अन्य उद्योगों की, खास कर अनाज और दाल प्रशोधन उद्योग की, रकमों को जोड़ने पर उत्पादन का मूल्य दो अरब रुपये में भी अधिक होगा। (देखिए तालिका ५।) दूसरे शब्दों में, कमीशन ने उपभोग की वस्तुओं का कुछ हद तक उत्पादन बढ़ाने में मदद की है जिसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि उसके गुणक प्रभाव से मुद्रा-स्फीति रोकने में सहायता भी पहुँचायी है।

उपसंहार

कोई भी अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था, जिसमें विस्तृत गैर-मुद्राकृत क्षेत्र मौजूद है, मुद्राकृत अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रिया में मूल्यों पर कुछ दबाव अवश्य डालेगी और मूल्यों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वे तब तक बढ़ते जायेंगे जब तक पूर्ण रोजगारी के पूर्व की मुद्रा-स्फीति की प्रक्रिया शुरू न हो जाय, जिसका परिणाम होगा वाजारों में उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी और अन्य स्थानों पर उत्पादन के साधनों की बेकारी। दूसरे शब्दों में, मूल्यों की साधारण वृद्धि जहाँ एक ओर किसी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में सहम्यक सिद्ध होती है, तीव्र वृद्धि हानिप्रद।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रकट होता है कि आय प्रसार की प्रक्रिया में गुणक के कार्य के लिए अथवा बड़ी हुई आर्थिक कार्यवाहियों या प्रतिरक्षा परिव्यय की वजह से उत्पन्न मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना एक परमावश्यक शर्त है। इस दृष्टि से भी खादी और ग्रामोद्योग जो योगदान दे सकते हैं वह काफी मूल्यवान हैं।

बम्बई . ५ दिसम्बर १९६३

पश्चिम बंगाल के कुटीर शिल्प

आशीश कुमार बसु

प्रस्तुत लेख में पश्चिम बंगाल के कुटीर शिल्पो का संक्षिप्त मूल्यांकन करते हुए उनकी विशेषताओं और उनके विकास के पीछे ऐतिहासिक दृष्टि से जिन शक्तियों का हाथ रहा है उन पर प्रकाश डाला गया है।

पश्चिम बंगाल के कुटीर शिल्प को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—परम्परागत शिल्पियों की जातियों का शिल्प, आदिवासियों का शिल्प और लोक-शिल्प (आदिवासी-शिल्प को कभी-कभी लोक-शिल्प का पर्याय समझ लिया जाता है) तथा वह शिल्प, जो लोगों की आधुनिक रूचि के विकास के साथ परिष्कृत हुआ है। पारम्परिक शिल्पकारों का



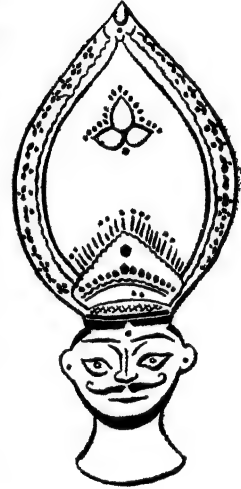
प्रथम वर्ग स्थानीय तौर पर सूत्रधार, कर्मकार, कुम्भकार, ततुवाय, कासा-कार, स्वर्णकार, शलार, चित्रकार, मालाकार आदि नामों से पुकारा जाता है। यह सब कारीगरों का वह वर्ग है, जो काष्ठ, पीतल, अष्ट धातु, चाक तथा करघों पर काम करते हैं या डमी तरह के अन्य धवों में लगे हैं। वंशानुक्रम से पिता से पुत्र ने सीखा और इस प्रकार उन्होंने इस समृद्धि-शाली विरासत को बचा कर रखा। बाकुडा, बर्दवान, बीरभूम, पुरलिया तथा मेदिनीपुर जिलों में एवम् पहाड़ी इलाकों में जो आदिवासी कारीगर पाये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे दक्षिण भारत, वर्मा आदि से समुद्री मार्ग द्वारा आ कर गंगा के मैदान के निचले प्रदेशों में बस गये। बर्दवान जिले में दरियापुर तथा बाकुडा के नूतन चट्टी के धातु शिल्पकारों ने आदिकालीन सिरे-पेरडू ढलाई को (मोम का आकार बना कर उस पर की

जानेवाली ढलाई) बचा कर रखा है, जो आज भी सम्बल, मयूरभज, लोहारडी आदि स्थानों के आदिवासियों के बीच प्रचलित है।

रेशमी तथा सूती वस्त्रों की छपाई, वर्तक गुड़ियों का निर्माण तथा बास पर नक्काशी करने का आधुनिक शिल्प भी वहाँ प्रचलित है।

पश्चिम बंगाल में इन दिनों कारीगरों का जो इतना भारी जमाव हो गया है, उसमें बंगाल के पश्चिम बंगाल के विभाजन का भी बहुत बड़ा हाथ है। गीतल पाटी बनानेवाले, बुनकर, शस्त्र की चूड़ियाँ बनानेवाले तथा कुम्भकार काफी बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल आये और धीरे-धीरे वही बस गये।

देश के अन्य शिल्प केन्द्रों की तरह पश्चिम बंगाल में भी शिल्प का विकास शासक राजाओं तथा नवाबों की राजधानियों के इर्द-गिर्द हुआ। इस प्रकार सूती और रेशमी वस्त्रोद्योग का विकास मालदा (पूर्व का गौर), मुशिदाबाद, बाकुडा तथा बीरभूम के आस-पास हुआ। हाथी दात की वस्तुओं का निर्माण, पीतल और अष्ट धातु की वस्तुओं का निर्माण, धातु की ढलाई तथा तेरा कोटा कुम्हारी आदि छोटे शिल्प शासकों के संरक्षण

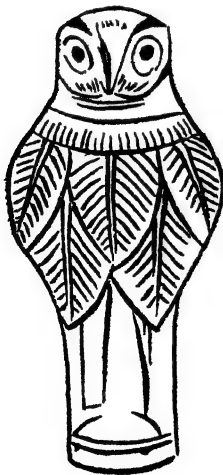


खिलौने

म पतपे। अंग्रेजी का ग्राफ्ट (Graft) यन्त्र (कलमकारी) का प्रायः समस्त ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रयोग होता है, किन्तु यहाँ सिर्फ उन्हीं उद्योगों की चर्चा की गयी है जिनका सम्बन्ध कला और शिल्प में है।

महत्वपूर्ण शिल्प केन्द्र

उन केन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं, जहाँ स्वाम-स्वाम शिल्प पद्धतियाँ के मूल तन्त्र देखने में आये हैं काष्ठ-शिल्प तथा काष्ठ के खिलौने नूतनग्राम तथा दैनहाट (वर्दवान), करिध्या (वीरभूम), काष्ठ-कार्य. हपनिया (बाकुडा) प्रस्तर शिल्प. मुमुनिया (बाकुडा) और दनहाट (वर्दवान) हाथी दात-शिल्प. बरहमपुर (मुशिदाबाद), रेशम-बुनाई मोनामुखी और विष्णुपुर (बाकुडा), तानीपाडा और करिध्या (वीरभूम) तथा मुशिदाबाद और मालदा के कुछ क्षेत्र, पीतल और अष्ट धातुशिल्प विष्णुपुर (बाकुडा), खगडा (मुशिदाबाद) और खगर (मेदिनीपुर), पीठ कार्य तथा डाक साज कुमारटोली (कलकत्ता) और कालीगज (नदिया), मिट्टी की मूर्तियाँ और खिलौने कृष्णनगर (नदिया), राजनगर (वीरभूम), जयनगर-मजिलपुर (२० परगना), नगजोल (मेदिनीपुर) और कुमारटोली (कलकत्ता),



काठ का बना उल्लूजुसा
बर्दवानी खिलौना

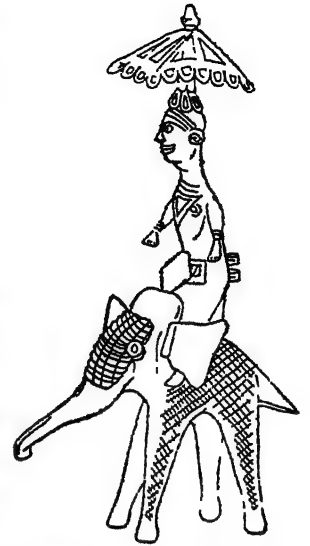
आभूषण एवम् रौप्य शिल्प कलकत्ता, चटाई-निर्माण: एगरा, मथग और रामनगर (मेदिनीपुर), शस्त्र-शिल्प विष्णुपुर (बाकुडा), कामिम बाजार (मुशिदाबाद) तथा बनूल (हावडा), और तेरा कोटा कुम्भकारी: पचमुरा और मोनामुखी (बाकुडा)।

इस सूची से पश्चिम बंगाल में शिल्पकारों के जमाव की एक मोटा-मोटी जानकारी मिलती है। उपर्युक्त श्रेणियों के ऐसे

सैकड़ों शिल्पकार वहाँ होंगे, जिनकी गणना हम सूची में नहीं आ पायी है।

स्वरूप-चित्रण, प्रारूप तथा रूपांकन

पश्चिम बंगाल की शिल्प परम्परा ने बहुत-से देशी और विदेशी श्रान्तों में स्वरूप-चित्रण प्रारूप तथा रूपांकन की कलाएँ अपनायी और कुशल शिल्पियाँ ने



ढोकरा धातु शिल्प-मिरे-पेरडू
ढलाई का एक नमूना।

पश्चिम बंगाल के शिल्प में स्वरूप-चित्रण का सम्बन्ध उस कला में जोड़ा जा सकता है, जो मूलतः फार्म की भूमि में आयी है।

फिर एक ऐसा वक्त आया जब गति अवरुद्ध हो गयी। मुहताज होकर शिल्पकारों ने दूसरे ध्वे अपना लिये। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से धीरे-धीरे जनता का सम्पर्क गाँवों और ग्राम्य शिल्पों से टूटना गया। पश्चिम बंगाल की सुप्रसिद्ध कथा बुनाई का कही नामोनिशा भी नहीं रह गया है, मेदिनीपुर, वीरभूम और बाकुडा के बर्तनों पर नक्काशी करनेवाले तथा ताम्र बनानेवालों का गौरव मिट गया और इसी तरह बहुत-से शिल्प समाप्त हो गये, जिनकी कृतियों के सुन्दर नमूने आज भी अजायबघरों में रखे हुए हैं, जो भारतीय जनता को उसके गौरवपूर्ण अतीत का सदेश देते हैं। बाकुडा में निर्मित घोड़े आज भी देश-विदेश में बैठक के कमरों की शोभा बढ़ाते हैं और छपे हुए रेशमी कपड़े न्यूयार्क तथा मास्को वासियों के सजे हुए घरों में चार चाद लगाते हैं। (रेखा चित्र श्री मुधीन बनर्जी द्वारा) कलकत्ता १० जुलाई १९६३

पंचायतों के साधन-स्रोत

पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय साधन-स्रोतों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा श्री के. मन्तानम् मी अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन जुलाई १९६३ में पेश किया। पंचायतों के साधन-स्रोतों से सम्बन्धित प्रतिवेदन का चौथा अध्याय यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विविध स्रोतों का वर्णन करते हुए उनमें दृष्टि करने के लिए उपाय सुझाये गये हैं।

भारत के लगभग ९.४ प्रति शत गाँवाँ में ३१ मार्च १९६२ तक विधिविहित पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी। ग्रामीण आबादी के हिसाब में करीब ३५ करोड़ २० लाख लोग इनके दायरे में आ चुके हैं। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल ही एक अपवाद रह गया है, जहाँ अब तक सिर्फ ३८ प्रति शत गाँव ही इस क्षेत्र के अन्तर्गत आ पाये हैं, लेकिन उम्मीद है कि उस राज्य के बचे हुए गाँवों में भी पंचायतों की स्थापना होने में अधिक समय नहीं लगेगा।

आबादी और क्षेत्र की दृष्टि में इन पंचायतों में काफी विभिन्नताएँ हैं। केरल की एक पंचायत की औसत आबादी जहाँ १५,४९३ है, उड़ीसा में ६,७४६, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम तथा पश्चिम बंगाल में ३,००० से ४,००० के बीच, मैसूर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में २,००० से ३,००० के बीच, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में १,५०० से २,००० के बीच, और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा दिल्ली में १,००० से १,५०० के बीच, एवम् उत्तर प्रदेश में १,००० से भी कम है। प्रत्येक राज्य की पंचायतों में भी विभिन्नताएँ हैं। मद्रास और मैसूर में पाँच हजार की आबादी और १० हजार रुपये वार्षिक से अधिक आयवाली पंचायत को शहर पंचायत की संज्ञा दी गयी है तथा आन्ध्र प्रदेश में उसे अधिसूचित पंचायत कहा गया है। गुजरात में ऐसी ग्राम पंचायतों को, जिनकी आबादी १० हजार से अधिक तथा ३० हजार से कम है, नगर पंचायत कहा जाता है। इस तरह का वर्गीकरण उपयोगी होगा, क्योंकि इन पंचायतों का

स्वरूप नगरपालिका से मिलता-जुलता-सा है और वे उपयुक्त प्रशासन कर्मचारी रख सकती हैं।

साधन-स्रोत तथा कर्तव्य

नाम एवम् वर्गीकरण में पर्याप्त विभेद के बावजूद विभिन्न राज्यों की पंचायतों के कामों में सादृश्य है। कुछ राज्यों में उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है अनिवार्य तथा विवेकाधीन। उदाहरणार्थ मद्रास में आठ अनिवार्य एवम् दस विवेकाधीन तथा आन्ध्र प्रदेश में १२ अनिवार्य और २७ विवेकाधीन कार्यों का विभाजन किया गया है। पंजाब में २७ कार्यों को अनिवार्य किया गया है और राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह सात विवेकाधीन कार्यों को भी अनिवार्य घोषित कर सकती है। महाराष्ट्र, केरल, मैसूर तथा अन्य कई राज्यों में कृषि, पशु-पालन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि जैसे प्रत्येक मद के अन्तर्गत कई काम रखे गये हैं। इस बात का आम उल्लेख किया गया है कि अपनी आर्थिक सीमाओं के अन्दर पंचायतें पीने के पानी की पूर्ति, सफाई, ग्रामीण सड़कों की देख-भाल, पाठशालाओं के भवन, सड़कों पर रोशनी तथा रेडियो, सामुदायिक सभा भवन व बालवाडियों आदि की व्यवस्था करें। दिवान सभाओं में कानून बनाते वक्त इस बात का अन्दाज लगाने की कोशिश की गयी है कि पंचायतों के अनिवार्य कार्यों की पूर्ति के लिए कम से कम कितना खर्च पड़ेगा और उसके लिए साधन-स्रोतों की व्यवस्था कैसे की जाय। अनिवार्य कार्यों के विस्तार के अनुसार वास्तविक साधन-स्रोत प्रायः सिद्ध होते हैं।

पचायतों के साधन-स्रोत प्रायः निम्न श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं

क उनके द्वारा लगाये जानेवाले कर्गों की आय,
ख उनके द्वारा लगायी गयी फीस तथा चुगी की आय,

ग सम्पत्ति, विनियोजन तथा लाभकारी कारोबार से आय,

घ राज्य सरकारों में प्राप्त सहायताएं, और
च जनता की ओर से प्राप्त अशदान।

अनिवार्य व ऐच्छिक कर

सभी पचायत अंगनियमों में पचायतों द्वारा कर लगाये जाने की व्यवस्था है। चन्द कानूनों में कुछ कर अनिवार्य हैं और कुछ ऐच्छिक। असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में सब कर ऐच्छिक हैं। आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा पंजाब में गृह-कर अनिवार्य है। इन राज्यों में महाराष्ट्र और पंजाब को छोड़ कर पेशा-कर भी अनिवार्य है। केरल और मद्रास में परिवहन-कर अनिवार्य है।

कराधान, निमदेह एक अप्रिय कार्य है। हम जिन पचायतों में गये, उनमें से कई में ऐसे तर्क उपस्थित किये गये कि चूकि केन्द्र और राज्य सरकारें उनके प्रकार के कर लगा रही हैं, इसलिए ऐसी हालत में पचायतों को जनता पर कर लगाने को बाध्य न किया जाय और वे सरकार से प्राप्त धन-राशि अथवा ऐच्छिक कर, फीस तथा अशदान यानी चन्दे आदि जैसे स्रोतों से ही अपने कार्य करें। किन्तु हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। हमारे खयाल से चन्द अनिवार्य करों का लगाना सिर्फ इसलिए ही जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पचायत को अपने स्वयम् के साधन-स्रोतों से थोड़ी-बहुत आय हो जाय, बल्कि इसलिए भी कि वह यह महसूस करे कि वह एक स्वायत्त संस्था है। गृह-कर, पेशा-कर तथा परिवहन-कर इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं।

किन्तु इसके साथ-साथ हम यह भी सोचते हैं कि पचायतें इन करों की किसी सन्त दर पर ही अडी न रहे। कर की अधिकतम और न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी चाहिए। जहाँ यह समझा जाय कि पचायत न्यूनतम कर लगाये, वहाँ उसे यह भी अधिकार होना चाहिए कि उसे वह अधिकतम सीमा तक बढ़ा सके।

गृह-कर का आधार

गृह-कर किसी मकान के पूजी मूल्य, उसके वापिक भाड़े या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य आधार पर लगाया जाता है। मद्रास में यह कर मकानों के पूजी मूल्य, भाड़ा मूल्य, मकान के रकबे या इनमें से किन्हीं दो अथवा अधिक आधारों को मिला कर लगाया जाता है। पूजी मूल्य पर कर लगाने के लिए छ माह की न्यूनतम दर उस मूल्य का द्वा प्रति शत और अधिकतम ३ प्रति शत है। मालाना मूल्य पर आठे वर्ष के लिए १ प्रति शत न्यूनतम तथा १० प्रति शत अधिकतम है। राज्य कानून में मकानों की नींव के विस्तार के आधार पर भी पक्की छत, छप्पर, खपरैल आदि की छत के अनुसार न्यूनतम व अधिकतम कर का निर्धारण है। किन्तु शहर पचायत तथा उसी तरह की बड़ी पचायतों को छोड़ कर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भाड़े के आधार पर कर लगाने की बात महज काल्पनिक ही होगी, इसलिए वहाँ पूजी मूल्य के आधार पर ही गृह-कर लगाना वाछनीय होगा।

किन्तु इस गृह-कर के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि किसी को छोड़ा जाय या नहीं। मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में किसी को छोड़ा नहीं गया है। किन्तु मध्य प्रदेश में १,००० रुपये की कीमत से कम मूल्य के सभी घरों पर कर नहीं लगाया जाता। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को, खास कर कच्चे मकानों में रहनेवालों को छोड़ दिया जाय, किन्तु हम महसूस करते हैं कि किसी को भी अपवाद न माना जाय। ऐसा सोचने का हमारा आधार सामाजिक और आर्थिक दोनों हैं। ढाई-सौ पये के मूल्यवाली एक

झोपड़ी पर $\frac{1}{2}$ प्रति शत की न्यूनतम दर से २५ नये पैसे या ५०० रुपये कीमतवाली पर ५० नये पैसे कर स्वरूप देने पड़ेंगे। हम नहीं समझते कि गरीब से गरीब परिवारों को भी इतना कम कर देने में कोई कठिनाई होगी। ऐसा कर दे कर वे महसूस करेंगे कि पंचायतो के कोष में वे प्रत्यक्ष रूप में योगदान दे रहे हैं और इसलिए अन्य निवासियों के लिए प्रदान की जानेवाली सेवाओं तथा सुविधाओं को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। गृह-कर की इस व्यापकता से प्रत्येक पंचायत को विभिन्न वर्गों के प्रत्येक घर की नवीनतम सूची रखनी पड़ेगी और फलस्वरूप उस सूची के आकड़े गाँवों की समृद्धि के विकास को सही रूप में पेश करेंगे। दूसरी तरफ किसी भी प्रकार की छूट से गृह-कर से होनेवाली आय कम हो जायेगी, खास कर उन गरीब गाँवों में जहाँ इस तरह की आय का काफी मूल्य होगा। अगर हमारा आयोजन वास्तविक है तो कालांतर में समस्त झोपड़ियों को पक्के मकानों में बदला जाना चाहिए। जिन राज्यों की पंचायतो का हमने अवलोकन किया, उनमें सन् १९६१-६२ में गृह-कर का मोटा-मोटी स्वरूप इस प्रकार था

राज्य	प्रति व्यक्ति नये पैसे
मैसूर	७३
आन्ध्र प्रदेश	६०
महाराष्ट्र	५२
मद्रास	३६
पंजाब	१३

इस सम्बन्ध में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, घरों का सही मूल्य निर्धारित करना। अनेक अधिनियमों में राज्य सरकारों को मूल्य निर्धारित करने के नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। हम समझते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में इस कार्य के लिए सरकार एक स्वतंत्र अभिकरण की स्थापना करने जा रही है। हमारी समझ से यह एक वाछनीय कदम है और जहाँ-कहीं भी ऐसी व्यवस्था की जायेगी, गृह-कर से होनेवाली आय काफी बढ़ जायेगी।

इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि समस्त राज्यों में बिना किसी छूट के अनिवार्य गृह-कर लगाया जाय। घरों के पूँजी-मूल्य के आधार पर उनकी वार्षिक न्यूनतम और अधिकतम दरें इस प्रकार हो सकती हैं

- क २५० रुपये तक के पूँजी मूल्य के घरों पर न्यूनतम २५ नये पैसे और अधिकतम १ रुपया,
- ख २५१ रुपये से ५०० रुपये तक के पूँजी मूल्य के घरों पर न्यूनतम ५० नये पैसे और अधिकतम २ रुपये,
- ग ५०१ रुपये से १,००० रुपये तक के पूँजी मूल्य के घरों पर न्यूनतम १ पया और अधिकतम ५ रुपये, और
- घ १००० रुपये से अधिक पूँजी मूल्य के घरों पर—वृद्धि के प्रत्येक ५०० रुपये अथवा उसके हिस्से पर न्यूनतम दर में ५० नये पैसे तथा अधिकतम में २५० रुपये अधिक।

शहर पंचायतो के लिए दरें अधिक हो सकती हैं।

कुछ राज्यों में किसी गाँव में साल में कुल मिला कर ६० दिनों तक कारबार करनेवाली किसी भी फर्म या कम्पनी पर या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो कम से कम ६० दिनों तक उस गाँव में कोई पेशा या कारबार करता है अथवा सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में नौकरी करता है और उस गाँव में रहता है, पंचायतें पेशा-कर लगा सकती हैं। यह कर उन लोगों पर भी लगाया जा सकता है जो उस गाँव में रहते हैं और पेन्शन पाते हैं। आम तौर से ३०० रुपये से कम वार्षिक आय पानेवाले इस कर से मुक्त रखे गये हैं। आन्ध्र प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिनियम में अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका में वर्णित न्यूनतम और अधिकतम दरें रखी गयी हैं

हम समझते हैं कि निम्न दरें उपयुक्त हैं। अनेक राज्यों में, हम देखेंगे कि सचिवान के अनुच्छेद २७६ में स्वीकृत अधिकतम २५० रुपये से बहुत कम अधिकतम निर्धारित किया गया है। इस हद तक कर लगाने से पंचायतों के अधिकारों को कानूनी तौर पर रोकने में हम कोई तर्क

नहीं देखते। ऊँची दरों के कर बड़ी आमदनी पर ही लगाये जा सकते हैं। निम्न तालिका में सालाना ५० रुपये की न्यूनतम दर उन्हीं पर लगायी जानी है, जिनकी वार्षिक आय १२,००० रुपये से अधिक हो। हम नहीं समझते कि इसमें किसी तरह की कठिनाई होगी। इसलिए हम इस बात की सिफारिश करते हैं

के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि पचायतो की रक्षान यह कर न्यूनतम करने की ओर रहती है, ताकि पड़ोसी इलाकों के साइकलवाले भी पजीकरण के लिए आकर्षित हो। इसलिए हम समझते हैं कि पचायत समिति न्यूनतम और अधिकतम दरों के बीच की दर निर्धारित करे और अपने समूचे क्षेत्र में एक समान रूप से उसे लागू

वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	न्यूनतम वार्षिक कर (रुपये में)	अधिकतम वार्षिक कर (रुपये में)
१	३०,००० रुपये से अधिक	२००	२५०
२	२४,००० रुपये से अधिक पर ३०,००० रुपये से ज्यादा नहीं	१५०	२००
३	१८,००० रुपये से अधिक पर २४,००० रुपये से ज्यादा नहीं	१००	१५०
४	१२,००० रुपये से अधिक पर १८,००० रुपये से ज्यादा नहीं	५०	१००
५	९,००० रुपये से अधिक पर १२,००० रुपये से ज्यादा नहीं	२४	५०
६	६,००० रुपये से अधिक पर ९,००० रुपये से ज्यादा नहीं	१२	२४
७	३,६०० रुपये से अधिक पर ६,००० रुपये से ज्यादा नहीं	८	१२
८	२,४०० रुपये से अधिक पर ३,६०० रुपये से ज्यादा नहीं	४	८
९	१,२०० रुपये से अधिक पर २,४०० रुपये से ज्यादा नहीं	२	४
१०	६०० रुपये से अधिक पर १,२०० रुपये से ज्यादा नहीं	१	२

कि इस परिच्छेद में पूर्व वर्णित श्रेणी के लोगों पर उपर्युक्त तालिका में बतायी गयी दर से पेशा-कर लगाया जाना चाहिए।

परिवहन-कर

तीसरा कर जिसे हम अनिवार्य कर देना उपयुक्त समझते हैं, परिवहन-कर है। आम तौर से मोटर गाड़ियों को इस कर से स्वतंत्र रखा जाता है, क्योंकि उनके लिए विशेष कर-कानून लागू है। इसके अतिरिक्त चन्द मामलों को छोड़ कर, मोटर गाड़ियों के मालिक आम तौर पर गाँव के निवासी नहीं होते और जहाँ-कहीं वे हैं भी वहाँ उनका पजीकरण शहरों में किया हुआ होता है। दोहरे कर से बचाव के प्रावधान की वजह से पचायत उन पर कर नहीं लगा सकेगी। किन्तु इसके अतिरिक्त बैलगाड़ियों, साइकल तथा अन्य परिवहनो पर कर लगाया जा सकता है। साइकलो पर कर लगाये जाने

करे। इस बात के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिए कि उस क्षेत्र की नगरपालिकाएँ भी उसी दर से कर लगाये। मद्रास में इस कर की न्यूनतम और अधिकतम दरें क्रमशः दो और चार पये वार्षिक हैं, मैसूर में सिर्फ अधिकतम दर तीन रुपये ही निर्धारित है, और उड़ीसा में वही दो रुपये की है। अन्य राज्यों में राज्य सरकारों पर यह बात छोड़ दी गयी है कि वे दर निर्धारित करें। हम मद्रास की दरों को उपयुक्त समझते हैं। बैलगाड़ियों के सम्बन्ध में एक सवाल उठता है कि किसी किसान की बैलगाड़ी पर कर लगाया जाय या नहीं। अधिकांश गाड़ियों के मालिक किसान होते हैं और वे उनसे खेती-बाड़ी से सम्बन्धित व उत्पादन को बाजारों में लेजा कर बेचने और खरीदने का काम लेते हैं। राजस्थान के कानून में खेती कार्य में उपयोग में लायी जानेवाली गाड़ियों को कर से मुक्त रखा गया है। गाँव की सड़क को अच्छी हालत में बनाय रखना बैलगाड़ियों के मालिकों

के लिए महत्वपूर्ण है।

इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि समस्त परिवहन पर, साइकलो सहित, परिवहन-कर लगाया जाय, पर न्यूनतम दर काफी कम होनी चाहिए — उदाहरणार्थ सालाना दो रुपये। हम इस प्रकार वार्षिक दरो की सिफारिश करते हैं

	न्यूनतम	अधिकतम
साइकले	२ रुपये	४ रुपये
बैलगाडियाँ	२ रुपये	१० रुपये

बैलगाडियो पर १० रुपये की अधिकतम दर इसलिए रखी गयी है कि किराये पर चलनेवाली गाडियो से पचायते अधिकाधिक आय प्राप्त कर सकें। अन्य परिवहतो पर कर की उपयुक्त दरे निर्धारित की जा सकती हैं।

पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सम्पत्ति और परिस्थिति-कर लगाये गये हैं, जो भूमि उप-कर (सेस) और गृह-कर का मिश्रण है। हमारी सिफारिश है कि उन्हे गृह-कर और भूमि-कर के शीर्षों से अलग-अलग रखा जाय, ताकि कर लगाने और वसूल करने में सहूलियत हो।

अन्य कर

इन करो के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों में पचायतों के इच्छानुकूल निम्न कर लगाने का प्रावधान है

क 'कोलागरम,' अथवा 'कटारुसुम' कर आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में माप-तौल या गिन कर बेचे जाने-वाले ग्रामीण उत्पादन पर लगाया जाता है। इस कर को वसूल करने की जिम्मेवारी, आम तौर से, केदारों को दे दी जाती है, जिनका काम बिक्री पर निगरानी रखना तथा कर सग्रह करना होता है। उस राज्य की बहुत-सी पचायतों के लिए यह आय का कीमती स्रोत है। गाँव की सीमा के अन्दर बेचे जानेवाले उत्पादनों पर मामूली कर भी काफी आय दे सकता है। हम सिफारिश करते हैं कि जहाँ-कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है,

इसे ऐच्छिक कर के रूप में शामिल किया जाय और लगाने के लिए पचायतों को प्रोत्साहन दिया जाय।

ख मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में चुगी (आकट्टाय) की व्यवस्था है। मैसूर में उसकी व्यवस्था सिर्फ शहर पचायतों तक ही है। बड़ी पचायतों के क्षेत्र में, सम्भव है, यह पर्याप्त आय का साधन सिद्ध हो सके किन्तु आम तौर से उसे प्रतिगामी कर समझा जाता है। ऐसी अवस्था में, जहाँ-कहाँ भी यह कर चालू है, वहाँ उसे तत्काल उठा देना तो व्यावहारिक नहीं है, किन्तु हमारी सलाह है कि सम्बद्ध सरकारें इस बात पर विचार करें कि क्या उसकी जगह कोई और प्रगतिशील कर लगाया जा सकता है।

तीर्थयात्री कर

ग महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा बिहार में पचायतों की इच्छा से तीर्थयात्री-कर लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के पूना जिले में देहू नामक स्थान पर, जो सत तुकाराम का जन्म स्थान है, हमने देखा कि पचायत को इस कर से इतनी अधिक आय हो जाती है कि उसने अन्य सभी कर-स्रोतों की अवहेलना कर दी है। हम समझते हैं कि चूकि तीर्थयात्री-कर धार्मिक प्रसिद्धि के कुछ ही स्थानों पर लगाया जा सकता है, इसलिए उसे लगाने के अधिकार पचायतों को न दिये जायें। जहाँ-कहीं भी उसे लगाना वाछनीय हो, यह काम पचायत समिति या जिला परिषद के जरिये होना चाहिए। उसकी आय का कुछ भाग सम्बद्ध पचायत को देना चाहिए तथा शेष पचायत समिति या जिला परिषद के क्षेत्र की जनता के समान लाभ के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इस सम्बन्ध में होनेवाले खर्च में भी सबको उपयुक्त हिस्सा बँटाना चाहिए।

घ जम्मू और कश्मीर के पचायत अधिनियम में पशुओं पर कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं। पंजाब राज्य की यात्रा के दौरान हमें पता चला कि भैसे तथा दूध देनेवाले अन्य मवेशियों पर कर लगाने से पचायतों को पर्याप्त आय हो सकती है। हमारा सुझाव है कि

राज्य सरकारे इस बात पर विचार करे कि क्या इस तरह का कर लगाने का अधिकार पंचायतो के कर लगाने के अधिकार में शामिल किया जा सकता है।

फीस और दरो को मोटा-मोटी तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है (क) सेवाओं के लिए फीस, (ख) लाइसेंस फीस, और (ग) जुर्माने और दण्ड की फीस।

विभिन्न प्रकार की फीस

क अनेक कानून जल-पूर्ति, गंदे नालों, सड़को की रोशनी तथा सफाई के लिए फीस लगाने के अधिकार प्रदान करते हैं। आम तौर से यह ऐच्छिक होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण सामाजिक सेवाएँ हैं, जिन्हें लोगों को प्रदान करने की पंचायतो से अपेक्षा की जाती है। पर जहाँ-कहीं भी जल-पूर्ति, बिजली की रोशनी और गन्दे नाले की व्यवस्था ऋण ले कर प्रदान की जाय, वहाँ उससे लाभ उठानेवाले समस्त लोगों से फीस लेना सही होगा। अगर किसी पंचायत में कई गाँव अथवा टोले आते हों और उक्त सेवाओं की व्यवस्था उसके क्षेत्र के कुछ ही हिस्से में है, तो उन लोगों को, जो उससे फायदा नहीं उठाते, फीस से मुक्त रखा जाय। साधारणतया, इस फीस की दर निर्धारित करने का आधार ऋण का ब्याज अथवा इस मद की देनदारी होनी चाहिए।

ख लाइसेंस फीस बेचे जानेवाले पशुओं के पंजीकरण, खाल तथा चमड़े के सग्रह, चाय, भोजनालय या विश्रान्ति-गृह या बाजार में बिक्री के लिए रखी गयी वस्तुएँ, नये भवनों के निर्माण, सार्वजनिक भूमि और सामुदायिक सम्पत्ति का उपयोग और जन-स्वास्थ्य के लिए अहितकर या खतरनाक व्यापार पर लगायी जाती है। हमारी राय है कि इस सम्बन्ध में पंचायतो के अधिकारों को यथा सम्भव विस्तृत बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की सरकार स्थिति पर फिर से गौर करे।

ग पंचायते निम्न स्थितियों में जुर्माने कर सकती हैं और दण्ड दे सकती हैं (१) अतिचार, (२) लाइ-

सेंस न लेना, तथा (३) प्रतिबन्धित वस्तुएँ रखना या उनकी बिक्री करना।

न्याय पंचायतो के लिए निधि

कुछ अधिनियमों में यह भी विधि है कि न्याय पंचायतो द्वारा किये गये जुर्माने ग्राम पंचायतो को दे दिये जाय। आम तौर पर इसके साथ ही ग्राम पंचायतो पर न्याय पंचायतो के खर्च वहन करने की जिम्मेदारी भी होती है। न्याय पंचायतो के अध्ययन के लिए गठित दल के प्रतिवेदन में सिफारिश की गयी है कि “ग्राम पंचायते कानूनन अपने कोष का एक अंश न्याय पंचायतो को हस्तांतरित करे या विकल्प रूप में राज्य सरकारें न्याय पंचायतो को समुचित अनुदान दे सकती हैं।” हम इस विकल्प सुझाव का समर्थन करते हैं। न्याय पंचायतो के कार्य का परिमाण विभिन्न स्थानों में कम या अधिक हो सकता है और अगर कहीं इतना अधिक हो कि एक पूरे समय के मंत्री की आवश्यकता हो या ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर काम का अधिक बोझ पड़े तो ऐसी अवस्था में दोनों के आय-व्यय को मिलाने से दोनों संस्थाओं के काम का नुकसान होगा। इसकी व्यवस्था पंचायत समिति के स्तर पर हो सकती है, जहाँ न्याय पंचायतो के वास्तविक खर्च के आधार पर अनुदान देने में सरकार के लिए आसानी होगी।

पंचायत राज संस्थाएँ राज्य सरकार के अभिन्न अंग हैं। इस वजह से यह ठीक ही है कि ग्राम-स्तर पर राज्य सरकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति की जिम्मेदारी जिसकी व्यवस्था पंचायते कर सकती हैं उन्हें दे दी जाय और उसे बरकरार रखने तथा सुधारने का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर रहे। हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई कि अनेक पंचायत अधिनियमों के अनुसार राज्य सरकारों की खाली जमीन पर अधिकार पंचायतो का है।

सरकारी सम्पत्ति पर स्वामित्व

अपने दौरो के दरमियान हमने देखा कि सरकारी

जमीन तथा अरक्षित वनों को पंचायतो को हस्तांतरित करने में, जहाँ यह हस्तांतरण विवेकाधीन है, राजस्व तथा वन विभाग के अधिकारी गण काफी आनाकानी करते हैं। हमें यह देख कर भी आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रीय और राज्यीय राजपथों के किनारे लगे पेड़ों में लगे फलों का उपभोग करने के अधिकार हस्तांतरित न करने की भी कोशिश की जाती है। कुछ राज्यों में मवेशियों के पानी पीने के तालाब भी राजस्व अधिकारियों के नियंत्रण में बने हुए हैं। हमारी सलाह है कि ये प्रवृत्तियाँ छोड़ दी जायें। जब तक सविशेष उल्लेख के साथ छोड़ न दिया गया हो, पंचायत क्षेत्र के अन्दर की निम्न सम्पत्ति, जिसका कोई निजी मालिक न हो, पंचायतो को हस्तान्तरित कर दी जाय (क) समस्त भूमि, (ख) समस्त पेड़, (ग) पोखर और तालाब तथा उनमें मछली पकड़ने के अधिकार, (घ) अरक्षित जंगलात, और (च) सराय, धर्मशाला, विश्राम-गृह, तथा अन्य भवनात।

यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने होंगे और प्रतिबन्ध लगाने पड़ेगे कि पंचायतें इस तरह की सम्पत्ति का दुरुपयोग, उसकी बर्बादी या अवहेलना न कर सकें। राजस्थान की एक पंचायत में यह देख कर हम दग रह गये कि वह आबादी की जमीन को बेच कर मिले रुपये से अपने चालू खर्च चला रही थी। मकान बनाने के लिए जमीन बेचना न्याय सगत हो सकता है, किन्तु उससे मिलनेवाली रकम पूँजी कोष में जानी चाहिए और उसका व्यय कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि पंचायत के लिए स्थायी सम्पत्ति का निर्माण हो। पंचायत द्वारा गाँव की किसी भी अचल सम्पत्ति का स्वत्व हस्तान्तरण निर्धारित अधिकारी की अनुमति अथवा स्वीकृति से ही होना चाहिए। इसी तरह पंचायत को अपने क्षेत्र में लगे पेड़ों के फलों का उपयोग करने का अधिकार हो, लेकिन पेड़ काटने के अधिकार के साथ सख्त शर्तें होनी चाहिए।

गाँवों में जलावन की व्यवस्था का यह हाल है कि वहाँ की सार्वजनिक भूमि तथा आरक्षित जंगलात से

लोग-बाग बेतहासा पेड़ काट रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जलावन की कमी हो गयी है। पेड़ों की छाया न होने के कारण ग्रीष्म काल में मनुष्य तथा मवेशियों को काफी कष्ट होता है। पंचायतो को प्रत्येक तरीके से अधिकाधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें इस बात का यकीन है कि अगर भूमि और वृक्षों से सम्बन्धित अधिकार पंचायतो को दे दिये जायें और उनकी देख-भाल की जिम्मेवारी भी पूर्णतः इन्हीं संस्थाओं की रहे, तो गाँव हरे-भरे हो जायेंगे और कालांतर में जलावन के मामले में भी गाँव स्वावलम्बी हो जायेंगे। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पंजाब में चकबन्दी के परिणाम स्वरूप चकबन्दी की गयी कुल भूमि का $\frac{1}{3}$ भाग सरकार का होता है तथा उस भूमि में से पाँच एकड़ भूमि पंचायत को मिलती है।

पंचायतों के लिए भूमि

कुछ राज्यों में गाँवों में खेती के लायक बहुत-सी ऐसी जमीन है जो खेती के लिए किसी को नहीं दी गयी है। ऐसी जमीन को पूर्णतः पंचायतो को हस्तान्तरित कर देना तथा भूमिहीन मजदूरों और अन्य लोगों के बीच उसे वितरित करने के लिए पंचायतों को ही एजेंट बना देना वांछनीय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में हमारी राय है कि प्रति व्यक्ति न्यूनतम एक सेट भूमि प्रत्येक पंचायत को हस्तान्तरित कर दी जाय, जिसे वह सामुदायिक सम्पत्ति के रूप में उपयोग में लायें, पर उसका स्वत्व हस्तान्तरित न करे, और शेष जमीन सरकार के पास बनी रहे। दूसरी तरफ यह भी स्थिति है कि समस्त जमीन स्वतंत्र लोगों की सम्पत्ति हो गयी है और पंचायतों के पास गाँव का कूड़ा-कंकट आदि जमा करने के लिए भी जमीन नहीं है। हम समझते हैं कि कम्पोस्ट खाद बनाना प्रत्येक पंचायत का कर्तव्य होना चाहिए। हम से कहा गया है कि मैसूर राज्य की एक साहसिक पंचायत कम्पोस्ट खाद की बिक्री से हर साल बड़ी आय कर रही है। हमारी सलाह है कि जहाँ-कहीं भी आवश्यक हो, राज्य सरकार भूमि

का अभिग्रहण कर कम से कम पाच एकड़ भूमि प्रत्येक पचायत को दे, जो मकान बनाने, कम्पोस्ट खाद तैयार करने, पेड़ लगाने, पौधों की कलम तैयार करने व अन्य ऐसे ही कार्यों में सामुदायिक सम्पत्ति के रूप में काम आवे।

मत्स्य-पालन से आय

जहा-कही भी ऐसे पोखर या तालाब हो जो ग्रीष्म काल में सूखते नहीं, वहाँ मत्स्य-पालन, ग्राम पचायतों की आय के लिए मूल्यवान् स्रोत हो सकता है। हमें यह जानकर सन्तोष हुआ कि उड़ीसा की सरकार ने समूचे राज्य में वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य-पालन का सगठन करने के लिए बड़ा दूरदर्शी कदम उठाया है। जहा-कही भी मछली पकड़ने के अधिकार रीत्यानुसार स्थानीय मछुओं की जाति को प्राप्त है, उनके अन्तर्गत रहते हुए अर्थात् उनकी अवहेलना न करते हुए पोखर या तालाबों की व्यवस्था के अधिकार पचायत को होने चाहिए। मछली पकड़ने के धंधे में लगे मछुओं तथा पचायतों के बीच आय का हिस्सा बटाने का कोई रास्ता निकाल लेना सम्भव है।

पचायतों इन पोखर और तालाबों की देख-रेख तथा मरम्मत का काम करेगी एवम् जिन व्यक्तियों हक में उक्त प्रकार के अधिकार हैं, उनसे खर्च वसूल करेगी। हम समझते हैं कि मवेशियों के जल पीने के पोखर, साधारणतया, पचायत की सम्पत्ति होने चाहिए। मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में पचायतों की आय के वे बड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये तालाब या पोखर पचायतों को सौंप देने चाहिए—अगर उनसे कोई आय न होती हो तो भी, क्योंकि यह अनिवार्यतः एक स्थानीय कार्य है। मवेशियों के जल पीनेवाले पोखर को उपयोग में लानेवालों पर न्यूनतम तथा अधिकतम कर लगाने के अधिकार पचायतों को मिलने चाहिए।

बाजार और मेले पचायतों की आय के अच्छे स्रोत होते हैं। अनेक अधिनियमों में राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे बाजारों को पचायत बाजारों या समिति बाजारों की श्रेणी में विभक्त कर सकती है। कुछ राज्यों में मवेशियों के बड़े वार्षिक मेले जिला परिषदों को सौंपे

गये हैं। यह वर्गीकरण आवश्यक और न्याय सगत है, क्योंकि कोई मेला या बाजार सिर्फ एक पचायत के ही काम नहीं आता। हम समझते हैं कि यह वर्गीकरण इस तरह के मेले और बाजारों की आय तथा जितनी आबादी को उससे फायदा होता हो उसी के आधार पर किया जाये। जो बाजार पचायत बाजार की श्रेणी में आवे, उनकी आय पचायतों को मिल सकती है। समिति या जिला परिषद बाजार की श्रेणी में आनेवाले बाजारों की आय का एक उपयुक्त हिस्सा उस पचायत को मिलना चाहिए जिसके क्षेत्र में मेला या बाजार लगता है। यह हिस्सा कुल आय का कुछ हो सकता है—ज्यादा से ज्यादा आबादी के प्रति व्यक्ति एक रुपये के हिसाब से। कुछ स्थानों पर बाजारों का नियंत्रण विशेष कानूनों के अनुसार गठित बाजार कमेटिया या समितिया करती है। अगर ये कानून न होते तो पचायतों और समितिया बाजारों की व्यवस्था करके या लाइसेन्स फीस लगा कर आय कर लेती। इसलिए यह उपयुक्त होगा कि जहा-कही भी बाजार कमेटिया या समितिया लाभ उठाती है या आय करती है, वहाँ उसका उपयुक्त हिस्सा समस्त पचायत राज सस्थाओं को भी मिलना चाहिए। हमारी सलाह है कि राज्य सरकारें इस विषय में सावधानीपूर्वक विचार करें। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि जहा-कही भी सम्भव हो सके, पचायतों और समितियों को बाजारों के सगठन में सक्रिय रूप से भाग लेने देना चाहिए।

राज्य सहायता की सीमा

समस्त स्थानीय सस्थाओं को कम-बेश राज्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। पचायत अधिनियमों में इसके लिए कई ढंग से व्यवस्था की गयी है। भूमि राजस्व और उस राजस्व पर स्थानीय उप-कर पचायतों को राज्य सहायता का महत्वपूर्ण अंश होता है। मोटे तौर पर उसे तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है (क) समस्त पचायतों को दिया जानेवाला आम अनुदान, (ख) समकारी निधि से अतिरिक्त आम अनुदान, तथा (ग) विशेष अनुदान।

विभिन्न राज्यों में यह सहायता इस प्रकार दी जाती है

क	आन्ध्र प्रदेश	—२५ नये पैसे प्रति व्यक्ति और उप-कर (सेस) के प्रति पये पर १६ नये पैसे।
ख.	बिहार	—भूमि राजस्व का ६३ प्रति शत (किन्तु अब तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है)।
ग	केरल	—बुनियादी कर (कानून में वर्णित है) का तीन-चौथाई (किन्तु इस कर के कानून की संवैधानिकता पर विवाद है, इसलिए वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया गया है)।
घ	मद्रास	—शहर पचायत के लिए भूमि-उप-कर के प्रति रुपये पीछे १० नये पैसे तथा ग्राम पचायतों के लिए भूमि-उप-कर से २० नये पैसे प्रति व्यक्ति।]
च	महाराष्ट्र	—बसूली के आधार पर भूमि राजस्व का ३० प्रति शत।
छ	मैसूर	—भूमि राजस्व का ३० प्रति शत।
ज	पंजाब	—भूमि राजस्व का १० प्रति शत।
झ	राजस्थान	—प्रति व्यक्ति २० नये पैसे, अधिकतम ४०० रुपये तक।

मुद्राक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) पर सरचार्ज लगाना पचायतों को दी जानेवाली राज्य सहायता का दूसरा रास्ता है। आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में सम्पत्ति विनिमय अथवा उपहार में दी गयी सम्पत्ति के दस्तावेज में उल्लिखित मूल्य या विक्री के मामले में प्रतिफल की रकम पर अथवा रेहन रखने पर प्राप्त रकम पर अधिकतम पांच प्रति शत सरचार्ज लगाया जाता है। केरल में सरचार्ज की अधिकतम दर चार प्रति शत है। यह सहायता कभी-कभी प्रति व्यक्ति अनुदान से अधिक होती है। पचायतों तथा अन्य शीर्ष सस्थाओं के लाभार्थ विभिन्न राज्यों में मुद्राक शुल्क पर सरचार्ज की दरों का वर्णन अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका में किया गया है।

पचायतों की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ करने के लिए मुद्राक शुल्क बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इस शुल्क की अदायगी करनेवाले खरीदार या रेहन रखनेवाले होंगे, इसलिए आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

मुद्राक-शुल्क के सम्बन्ध में एक प्रश्न है कि यह पूर्णतः पचायत को ही मिले, जैसा कि मद्रास में होता है, या पचायत राज की अन्य सस्थाओं को भी उसका हिस्सा दिया जाय। मद्रास में एक समूचे पचायत सघ क्षेत्र के लिए मुद्राक-शुल्क की बसूली की जाती है और बाद में भूमि राजस्व के सग्रह के आधार पर पचायतों में उसका वितरण किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में पचायत अपने क्षेत्र में सग्रह किये गये शुल्क का ६ हिस्सा प्राप्त करती है और शेष भाग का समिति तथा जिला परिषद के बीच बराबर के हिसाब से बटवारा होता है। लेकिन हम ऐसा हमसूस करते हैं कि उसका समिति और उसकी पचायतों के बीच साम्य-मूलक बटवारा होना चाहिए। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि

- १ पचायत राज सस्थाओं के लाभ के लिए मुद्राक-शुल्क पर सरचार्ज लगाया जाय जो सम्पत्ति के मूल्य पर पांच प्रति शत से अधिक न हो,
- २ यह सरचार्ज राज्य सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए तथा राज्य के मुद्राक-शुल्क के साथ ही बसूल करना चाहिए, और
- ३ एक पचायत समिति के क्षेत्र के अंदर सग्रह किये गये शुल्क को समिति और उसकी पचायतों के बीच साम्य-मूलक आधार पर वितरित करना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण कर, जिसका आगम पूर्णतः या अंशतः पचायतों अथवा समितियों को दिया जा सकता है, राज्य मनोरजन कर है। मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में यह व्यवस्था है कि किसी पचायत सघ समिति के क्षेत्र में सग्रह किये गये मनोरजन कर का ९० प्रति शत

हस्तांतरित कर उस पचायत सच समिति और उसकी पचायतों के बीच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार वितरण किया जाय। फिलहाल पूरा अश पचायतों को दिया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और मैसूर के अधिनियमों में पचायतों को मनोरजन कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं, जो आम तौर से सिर्फ प्रदर्शन कर ही हैं। हमारी सलाह है कि राज्य सरकार द्वारा लगाया गया मनोरजन कर पूर्णतः या अश पचायतों तथा समितियों के साथ बाँटा जाय। इसके अतिरिक्त वे प्रदर्शन कर भी लगा सकती हैं।

अनेक राज्यों में भूमि राजस्व और उप-करो के आधार पर होनेवाली आय की असमानताओं को दूर करने के लिए समकारी अनुदान दिये जाते हैं। इस आधार पर उपजाऊ और मिचिन भूमिवाले क्षेत्रों की पचायतों को अवश्य ही अन्य क्षेत्रों से अधिक आय होगी। महाराष्ट्र में भूमि राजस्व के ३० प्रति शत के बराबर के अनुदान तथा प्रति व्यक्ति एक रुपये की दर के हिसाब से जो रकम आती है उनका फर्क राज्य सरकार पूरा करती है। आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति २५ नये पैसे

राज्य	आगम प्राप्त करनेवाली संस्था	अधिनियम में निर्धारित सीमा
आन्ध्र प्रदेश	पचायत समिति परिषद	—ऐसी दर पर जो सरकार द्वारा मुकर्रर हो, लेकिन सम्पत्ति की कीमत पर पाँच प्रति शत से अधिक नहीं।
असम	पचायत	—निर्धारित समय पर और तरीके से लगाया जायेगा।
गुजरात	तालुका पचायत	—तालुका पचायत / जिला पचायत की दख्खिस्त पर लगाया जायेगा लेकिन उसकी दर मुद्राक शुल्क के १५ प्रति शत से अधिक नहीं होगी।
	जिला पचायत	—जिला पचायत की दख्खिस्त पर लगाया जायेगा जिसकी दर मुद्राक शुल्क के १० प्रति शत से अधिक नहीं होगी।
केरल	पचायत	—सरकार द्वारा निर्धारित की जानेवाली दर पर लगाया जायेगा, किन्तु सम्पत्ति की कीमत के चार प्रति शत से अधिक नहीं होगा।
मध्य प्रदेश	जनपद पचायत	—सम्पत्ति के मूल्य पर $\frac{3}{4}$ प्रति शत बढ़ाने का अधिकार।
मद्रास	पचायत	—सरकार द्वारा निर्धारित की जानेवाली दर पर, किन्तु सम्पत्ति के मूल्य के पाँच प्रति शत से अधिक नहीं।
महाराष्ट्र	जिला परिषद	—सम्पत्ति के मूल्य पर $\frac{3}{4}$ प्रति शत।
मैसूर	तालुका मण्डल	—ऐसी दर पर जो सम्पत्ति के मूल्य की पाँच प्रति शत से अधिक न हो।
पंजाब	पचायत	—सरकार द्वारा निर्धारित की जानेवाली दर पर, जो दो प्रति शत से अधिक न हो।

कुछ राज्यों में पचायत के मंत्री का पूर्ण अथवा आंशिक वेतन दे कर उस रूप में राज्य सहायता दी जाती है। इस सम्बन्ध में हम मशविरा देते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति अनुदान (बशर्ते कोई हो) से आवश्यकता पूरी न होती हो तो यह सहायता प्रयोजनात्मक अनुदान के रूप में होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि मंत्री का वेतन प्रत्यक्षतः पचायत ही दे।

के हिसाब से जो रकम होती है, वह पिछड़ी हुई पचायतों के बीच वितरित करने के लिए समकारी कोष के रूप में रखी जाती है। मैसूर में ३० प्रति शत भूमि राजस्व अनुदान से होनेवाली आय, जिन पचायतों की प्रति व्यक्ति ४५ नये पैसे के हिसाब में होनेवाली रकम से कम पड़ती हो, उन्हें इस अन्तर के बराबर सहायता दी जाती है।

उड़ीसा में केदू-पत्ती की विक्री में होनेवाली आय पचायतो तथा पचायत समितियों के बीच बाँटी जाती है। हमारी सलाह है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी, जिनके यहाँ भी राजस्व का यह स्रोत है, उड़ीसा का अनुकरण करने की बात पर विचार कर सकती हैं।

मद्रास की सरकार पचायतो को अधिक दर पर कर लगाने तथा उन्हें समय पर वसूल करने की बात को प्रोत्साहित देने के लिए पचायतो द्वारा गृह-कर के रूप में वसूल की गयी रकम के बराबर अनुदान देती है। कुछ राज्यों में अपना फर्ज अच्छी तरह निभाने के लिए, जिसमें राजस्व का सग्रह भी शामिल है, पचायतो को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गयी है। हम समझते हैं कि मद्रास से अधिक विस्तृत आधार पर उपयुक्त अनुदान देने से, किन्तु अधिक उदार दर पर, पचायतो के अन्दर करो की दर न्यूनतम से ऊपर उठाने तथा समय पर उसे वसूल करने की प्रेरणा जागृत होगी। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि पचायतो को उनके द्वारा लगाये गये पूरे कर (बकाया रकम छोड़ कर) को आधार मान कर उसके तुल्य अनुदान दिया जाय। अगर एक साल के अन्दर ७५ प्रति शत वसूली कर ली जाती है तो उस वसूली पर १५ प्रति शत के बराबर रकम तुल्य अनुदान के रूप में दी जाय और उसके बाद प्रति पाच प्रति शत की वसूली पर उक्त प्रकार के अनुदान में भी एक प्रति शत की वृद्धि की जाय। पिछड़े हुए क्षेत्रों की पचायतो के लिए यह अनुदान और भी उदार आधार पर दिया जाना चाहिए।

अनुरक्षण सहायता

इन समस्त सहायताओं के बावजूद हमें खेद के साथ इस बात का उल्लेख करना पड़ता है कि अधिकांश पचायतो की कुल आय आवश्यकता से काफी कम है। कि उनका आधार मजबूत हो सके। यह स्पष्ट है कि आवश्यक प्रशासनात्मक कर्मचारियों के बिना कोई भी ग्राम पचायत प्रभावकारी ढंग से अपना काम नहीं कर सकती। स्थानीय करो तथा अन्य तरीकों

में पचायते अपने आपके स्रोतों का विस्तार करने के प्रयासों में तब और भी अधिक सफल हो सकेगी, जब कि जनता यह समझ ले कि उस आय का उपयोग उनकी सुख-सुविधाओं के लिए होगा, न कि सिर्फ प्रशासनिक खर्चों के लिए। इसलिए, हम मशविरा देते हैं कि प्रत्येक पचायत को प्रति व्यक्ति एक रुपये के न्यूनतम आधार पर अनुरक्षण सहायता दी जाय और केन्द्र तथा राज्य की सरकारें इस सहायता में बराबर अंश का योगदान करें। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि अब तक भारत सरकार ने इस कार्य के लिए पचायतो को कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी है। किन्तु हम अच्छी तरह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों की तरह ही इस बात के लिए व्यग्र है कि पचायत राज की ये बुनियादी इकाइयाँ न्यूनतम आय के अभाव में कमजोर न होने पायें अथवा खण्डित न हो जाय।

केन्द्रीय सहायता

हम नहीं सोचते कि बलवतराय मेहता समिति के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त उत्प्रेरणा के बिना सारे भारत में इतने व्यापक पैमाने पर ग्राम पचायतों की स्थापना हो पाती। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का ताल्लुक है, यह अनुदान—जिस पर करीब १२ करोड़ रुपये सालाना खर्च होंगे—तीसरी पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए सविधान के अनुच्छेद २८२ के अनुसार मौजूदा समय में राज्यों को दिये जा रहे अनुदान के साथ पूर्णतः या अंशतः समायोजित किया जा सकता है। यह कार्य जिस सीमा तक होगा, वही केन्द्रीय सहायता होगी तथा इस प्रकार राज्यों को दी जानेवाली केन्द्रीय सहायता में पचायतो के लाभार्थ दी जानेवाली रकम का अलग उल्लेख रहेगा। पचायतो को राज्य सरकारों की ओर से आर्थिक सहायता ऊपर वर्णित विभिन्न रूपों में दी जाती है, किन्तु जहाँ-कहीं भी यह सहायता न्यूनतम ५० नये पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से कम पड़ती है, उसे पूरी करने के बाद ही राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकने के योग्य हो सकेगी।

हमारी सलाह यह नहीं है कि कोई भी राज्य पचायतो को प्रति व्यक्ति ५० नये पैसे के हिसाब से सहायता दे कर ही सतुष्ट हो जाय। जब तक पर्याप्त रकम की व्यवस्था नहीं हो जाती, पचायते अपने दायित्व को निभा सकने में असमर्थ रहेगी। फ्रान्स, ब्रिटेन तथा कुछ अन्य देशों में इन पचायतों जैसी स्थानीय संस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय ५० रुपये से १०० पये तक है। अपनी पचायतों की औसत आय तो प्रति व्यक्ति पांच पये तक पहुँचाने में ही हमें काफी वक्त लग जायेगा। हमारा विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक रुपया न्यूनतम सहायता तो प्रत्येक पचायत को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से मिलनी ही चाहिए। हमें इस बात में कतई सदेह नहीं है कि अगर यह सिफारिश मजूर कर ली गयी तो सारे देश की पचायतों में एक मनोवैज्ञानिक क्रान्ति उत्पन्न हो जायेगी और तब वे अपने स्रोतों से आज की अपेक्षा अधिक आय प्राप्त कर सकने में समर्थ होगी तथा जैसा कि हमने ऊपर कहा है, वे अनिवार्य और ऐच्छिक करो से पूर्ण लाभ उठाने की चेष्टा करेगी।

उल्लेखनीय सफलता

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उल्लेखनीय सफलता यह है कि विद्यालय भवन, सड़के, दवाखाना, सार्वजनिक शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचायत घर आदि जैसे विकास कार्यों के लिए पर्याप्त स्थानीय योगदान प्राप्त करने की प्रथा सामान्य हो गयी है। यह इसलिए सम्भव हो सका है कि सरकार की ओर से भी उसके तुल्य सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। हम इस बात के लिए उत्सुक हैं कि यह तरीका कायम रखा जाय। कुछ राज्यों के पचायत कानूनों में मजदूरी-कर की विधि है, जोकि नकद मुजरा किया जा सकता है।

फिर पचायतों को यह भी अधिकार दिया गया है कि किसी खास उद्देश्य के लिए वे भूमि-कर आदि के आधार पर विशेष कर लगा सकती हैं। हाल ही में, सामुदायिक विकास मंत्रालय की प्रेरणा से 'सुरक्षा श्रम बैंक' की स्थापना की गयी है जिनमें ग्रामीण जनता के श्रम का हिसाब रखा जाता है। हम समझते हैं कि इन समस्त प्रयासों को विवेकपूर्ण बनाया जाय। इसके लिए हम निम्न सिफारिश करते हैं

उपसंहार

समस्त राज्यों की पचायतों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे किसी विशेष विकास परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए भूमि-राजस्व, गृह-कर या अन्य करों के आधार पर विशेष कर लगा सके। यह प्रकार सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध होना चाहिए, लेकिन प्रस्ताव के जरिये उसे पुनः नवीन किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि योजना को स्वैच्छिक योगदान के रूप में प्राप्त धन और श्रम के बल पर पूरा किया जाय। अगर यह योगदान पर्याप्त न हो तो 'सुरक्षा श्रम बैंक' श्रम कर या नकद अथवा श्रम के रूप में दिये जा सकनेवाले विशेष कर लगाने का मार्ग अपनाना चाहिए। स्वैच्छिक अशदान को इन करों के साथ समायोजित किया जा सकता है। यह देखना भी जरूरी है कि इस तरह की स्वैच्छिक, अनिवार्य या दोनों प्रकार की अत्यधिक मांगों का जनता पर अधिक बोझ न पड़े। इसके साथ-साथ इस बात का भी स्मरण रखना है कि बेकार श्रम को उपयोगी व सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में बदलना हमारे गावों के विकास का सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग है।

ग्राम सफाई

जागेइवर गोपाल श्रीखण्डे

ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने की दृष्टि से मानव मल-मूत्र को योग्य ढंग से तथा सस्ते में उपयुक्त स्थान में पहुँचाने की कितनी जरूरत है, इस विषय पर विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है। इसी समस्या का हल करने में हर एक को सहज ही उपलब्ध होने-वाला सस्ता जल-बंद शौचालय सहायक होना चाहिए।

यह सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष बहुत लोग हैजा, मियादी बुखार और सग्रहणी जैसी महामारियों के शिकार हो चल बसते हैं और लाखों लोग अपग हो जाते हैं। इसी प्रकार आत-आकीर्णन भी बड़ी बीमारी है। अस्सी प्रति शत से अधिक ग्रामीण इससे पीड़ित हैं। आतों पर आक्रमण करनेवाली जोक भोजन खा जाती हैं और उसके कारण मनुष्य धीरे-धीरे दुर्बल होने लगता है। यह रोग कब्ज के कारण होता है। शहरी कूड़े-कचरे तथा मानव मल-मूत्र से गर्म खमीर प्रक्रिया के जरिये खाद बनाने पर भी आकीर्णन का भय रहता है।

वातावरण की स्वच्छता

स्वच्छता तथा सफाई ने, विशेषकर वातावरण की, शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आयोजन नहीं होने के कारण गाँवों और शहरों का बेतरतीब विकास हुआ, जोकि अपनी बढ़ती आबादी के लिए उपयुक्त सफाई व्यवस्था नहीं कर सके। फिर, यातायात के विकास ने लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना बहुत ही सहज कर दिया है और यदि समाज के चन्द लोग भी स्वास्थ्य-नियमों को नजरदाज करते हैं तो महामारी फैल सकती है। अतः हमारी आबादी के बढ़ते जाने के साथ ही साथ वातावरण की स्वच्छता पर ध्यान देना उतना ही जरूरी हो जाता है।

वातावरण की स्वच्छता बनाये रखने के लिए अत्यावश्यक है कि मानव मल-मूत्र का सफाई के साथ परित्याग किया जाय, पीने के पानी में कीड़े न पड़ सकें, उपयुक्त

नालियों बनायी जायें, मक्खियों और मच्छरों पर नियंत्रण पाया जाय और अन्न तथा वातावरण के सम्बन्ध में स्वास्थ्य-नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में मल-मूत्र का सफाई के साथ परित्याग तथा पानी की पर्याप्त पूर्ति जन स्वास्थ्य को बनाये रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण समस्या रही है और अब भी बनी हुई है। मल-मूत्र के बेढंगे परित्याग और पीने के गंदे पानी के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष काफी लोग जठरांत्रिक बीमारी में पीड़ित होते हैं और उनमें से बहुत-से मर जाते हैं।

आकीर्णन

हमारे गाँवों में, जहाँ कि हमारी ८० प्रति शत आबादी रहती है, दूसरी बड़ी बीमारी आकीर्णन के कारण होती है, जोकि मनुष्य की शक्ति को क्षीण करती है। इससे पीड़ित लोग दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते। इन बीमारियों को दूर करने का एक ही सतोषजनक उपाय है और वह है मल-मूत्र को सुरक्षित जगह में पहुँचाना।

इस प्रकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण की स्वच्छता ही वह आधार है, जिससे जन-स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति की जा सकती है। वातावरण स्वच्छ न होने पर समाज के स्वास्थ्य-स्तर में किसी सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार देश में जन स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त स्वच्छता और सफाई अति आवश्यक पहलू है। दूषित वातावरण के कारण होने-वाली बीमारी और मृत्यु की रोकथाम जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करनेवालों के लिए प्रमुख कार्य होना

चाहिए, जिन्हें कि वे अभिनव सफाई व्यवस्थाओं के जरिये दूर कर सकते हैं।

यह आम धारणा है कि ग्रामीण जल पूर्ति और सफाई योजनाएँ बनाना व कार्यान्वित करना सरल है तथा उनके कार्यान्वय में किसी तकनीकल दक्षता की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय-समय पर यह पाया गया है कि क्षेत्र में काम करनेवाली विभिन्न संस्थाओं के विचार-वैभिन्य और बिना स्तरीय पद्धतियों को अपनाये ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के भिन्न तरीकों के कारण ही ये योजनाएँ असफल रही हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए जबकि जल पूर्ति और नाली योजनाओं के लिए निश्चित मानक और डिजाइन हो सकती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति के लिए किसी खास किस्म की डिजाइन व मानक का सुझाव देना तथा उसे कार्यान्वित करना कठिन है।

नल के जरिये जल पूर्ति

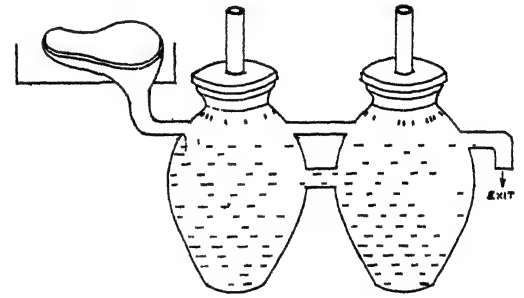
इन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव के नक्शे, आबहवा और सामाजार्थिक अवस्थाओं के अनुसार बनाया और कार्यान्वित किया जाता है, जोकि जगह-जगह पर बहुत भिन्न हैं। अतः योजनाओं के बनाने में अनुभवी जन-स्वास्थ्य इंजीनियर की सहायता बहुत ही आवश्यक है, ताकि लोग उन्हें स्वीकार कर सकें और जोकि उनकी आर्थिक पहुँच के अन्दर भी होगा। शहरी योजनाओं के मामले में इस तरह की विशिष्ट समस्याएँ नहीं उठेंगी, परन्तु ग्रामीण योजनाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

नल के जरिये जल पूर्ति का कितना महत्व है तथा यह कितना बाछनीय है, इसे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु साथ ही यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रामीण जल पूर्ति की समस्या का यही एक मात्र हल है। बहुधा यह देखा जाता है कि ग्रामीण नल जल-पूर्ति व्यवस्था को उदारतापूर्वक नहीं अपनाते, क्योंकि इससे

गाँव की कच्ची गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है।

सस्ते और स्वच्छ शौचालय

ग्रामीण सफाई के क्षेत्र में मानव मल-मूत्र को उपयुक्त जगह में भेजने की व्यवस्था की जा रही है और ग्रामीण घरों के लिए उपयुक्त तथा प्रभावकारी जल-बन्द शौचालय भी बनाये गये हैं। परन्तु ये शौचालय महंगे हैं और इनमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसकी कमी है। गाँव के प्रत्येक घर में, जहाँ कि अब पानी उपलब्ध है, चार से पांच व्यक्तियों के लिए सस्ता और जल-बन्द शौचालय (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) उपलब्ध करना



सस्ता, स्वच्छ जल-बोद्धित शौचालय

सम्भव है। इस शौचालय के ये लाभ हैं (१) सरल और सादा है, (२) सस्ता है—कीमत ३० रुपये, (३) बहुत कम सीमेंट की आवश्यकता होती है, (४) संपूर्णतः ग्रामोद्योगी उत्पादन से ही बनता है, (५) ढक्कन को सहज ही हटाया जा सकता है और मल-मूत्र निलकाने के बाद फिर अपनी जगह बैठा दिया जा सकता है, और (६) गढ़ा पानी जमीन के नीचे बनी ६ इंच व्यासवाली नाली के जरिये, जोकि गावों में कुम्हारों द्वारा बनायी जाती है, खेत में पहुँचाया जा सकता है। मिट्टी के बने बर्तनों पर सीमेंट की पर्त चढ़ाना आवश्यक है, ताकि उनमें से पानी नहीं रिसे। ऐसा नहीं करने से पीने के पानी का स्रोत गढ़ा हो सकता है।

वर्षा १० मई १९६३

गुड़ और खाण्डसारी उद्योग

दीना नाथ दुबे

गुड़-खाण्डसारी उद्योग उत्तर प्रदेश में एक कठिन समय में हो कर गुजर रहा है। उद्योग को दृढ़ आधार पर प्रतिष्ठापित करने के लिए यह आवश्यक है कि गुड़-खाण्डसारी के उत्पादन में उन्नत साधन-समरजाम व तकनीकों के व्यवहार को लोकप्रिय बनाया जाय ताकि वे ज्यादा दिनों तक टिक सके और स्तर-निर्धारण, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था की जा सके।

देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के कृषि-प्रधान उद्योगों में गन्ने से गुड़ और खाण्डसारी बनाना एक मुख्य ग्रामोद्योग है अथवा यो कहिये कि यह खेती के बाद ऐसा धंधा है जिसके माध्यम से ग्रामीणों और बैलों को चार-पाँच महीने रोजगार मिल जाता है, जबकि उनके पास कोई काम नहीं होता। गाँवों में गन्ने से गुड़, राब और खाण्डसारी बनाने की कई विधियाँ हैं। साधारणतया कोल्हू से चार व्यक्तियों को रोजी मिलती है। सन् १९५६ की पशु-गणना के अनुसार समूचे देश में कुल ५,४४,९८८ बैल-चालित कोल्हू हैं। इनमें से ३,०५,१५६ कोल्हू तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही चलते हैं। यदि चार व्यक्तियों के हिसाब से रोजगारी का तखमीना निकाला जाय तो अकेले उत्तर प्रदेश में १२,२०,६२४ लोगों को घर बैठे रोजगारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार २३,२९१ शक्ति-चालित कोल्हू (पावर क्रशर) तथा ८०० सेन्ट्री-फ्यूगल हैं। इन सबसे देश भर में ३० लाख लोगों को तथा उत्तर प्रदेश में २० लाख व्यक्तियों को मौसमी रोजगारी मिलती है।

विश्व की जितनी जमीन पर गन्ने की खेती होती है, उसकी ३० प्रति शत भूमि भारत में है, किन्तु देश की कृषि भूमि का यह दो प्रति शत है। गन्ने की अत्यधिक फसल का कारण यह है कि पैदावार का ५५ प्रति शत बैल से चलनेवाले कोल्हूओं से पेरा जाता है। कुल गन्ना-उत्पादन का ६० प्रति शत भाग गुड़-खाण्डसारी बनाने, ३० प्रति शत चीनी तथा शेष १५ प्रति शत चूसने व बीज के काम आता है।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग (द्वितीय पंच वर्षीय योजना) समिति ने लिखा था 'गुड़ उद्योग खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि उससे बहुत-से लोगों को रोजगार मिलता है।' देश के बहुत-से हिस्सों में गुड़ उद्योग को दो मुख्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें एक दिक्कत तकनीकों का सम्बन्धी है, जहाँ अविकसित औजारों व उत्पादन के पिछड़े तरीकों का प्रचलन है। दूसरी दिक्कत बाजार व्यवस्था सम्बन्धी है जहाँ माल रखने के स्थान यानी अच्छे गोदामों व गैरह की कमी, पैकिंग और उत्पादन, प्रमाणीकरण व स्तर निर्धारण आदि की दिक्कत उसे उठानी पड़ती है। इसलिए गुड़ उद्योग के विकास कार्यक्रम का एक खास उद्देश्य यह होना चाहिए कि तकनीकी तौर पर बिजली से चलनेवाले कोल्हू जारी किये जाय और उन्नत प्रकार के कड़ाह तथा अन्य साधन प्रयोग में लाये जाय एवम् गुड़-खाण्डसारी इस प्रकार बनायी जाय कि वह ज्यादा दिनों तक टिक सके और भाण्डारीकरण, पैकिंग व स्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण आदि की ठीक व्यवस्था की जा सके।'

पृष्ठभूमि

गुड़ और खाण्डसारी का एक-दूसरे से अटूट सम्बन्ध है। जब गुड़ की कीमते गिरती हैं तो खाण्डसारी बना कर होनेवाली हानि को रोकने की चेष्टा की जाती है। कुछ लोग गुड़-खाण्डसारी को चीनी उद्योग के विकास में बाधक बताते हैं, किन्तु वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि दश के अधिकांश लोगों की प्रति व्यक्ति दैनिक

आय २५ नये पैसे भी नहीं हैं और ऐसे लोगों की मीठे सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति गुड-खाण्डसारी से ही होती है। इसके अलावा लाखों लोगों को इस उद्योग से रोजगार मिलता है, वह अलग।

हाल ही में इस उद्योग के सामने एक बाधा आयी जिससे इन चार दुष्परिणामों को प्रश्न्य मिला (१) गन्ना उत्पादकों में क्षोभ का उत्पन्न होना, (२) गुड-खाण्डसारी के उत्पादन में गिरावट, (३) उद्योग में लगे लोगों का बेरोजगार होना, और (४) गन्ने का उत्पादन भी कम होना। गन्ना उत्पादकों के लिए चीनी मिलों को गन्ना बेचना असुविधाजनक रहा है, उन्हें कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। अतः यदि गन्ना उत्पादकों को गन्ना देने के लिए अनिवार्य रूप से विवश किया जाता है तो निस्सन्देह चीनी मिलें उनकी बेबसी का फायदा उठायेगी और वैसी अवस्था में गन्ना उत्पादकों को जो परेशानी होगी उसका स्पष्ट परिणाम यह निकलेगा कि गन्ने का उत्पादन कम हो जायेगा। परिणाम-स्वरूप यह खतरा है कि गुड-खाण्डसारी उद्योग को अभीष्ट गन्ना नहीं मिल पायेगा, जिससे उद्योग का उत्पादन घटने के साथ ही साथ इसमें लगे लोगों के समक्ष बेकारी की समस्या भी खड़ी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मौजूदा नियंत्रणों से गुड बनाने में भी शिथिलता आ गयी है, क्योंकि गुड की लदान बन्द होना से भाव गिर गया है तथा जिन राज्यों में गुड जाता था वहाँ गुड न पहुँचने से भाव बेतहाशा बढ़ गये हैं और चोर बाजारी जैसी बुराईयों बढ़ गयी हैं।

संतुलित विकास

देश की प्रगति के लिए गुड-खाण्डसारी और चीनी उद्योग सभी के संतुलित विकास की आवश्यकता है। चीनी मिलों के समक्ष गन्ने की पूर्ति का जो प्रश्न है वह गन्ने की सघन खेती के माध्यम से हल किया जाय तो वैसा करना किसान, चीनी मिलों और देश तीनों के लिए हितकर होगा। गुड-खाण्डसारी का विकास इस तरह किया जाय कि देश में आंतरिक खपत के लिए उसका उत्पादन बढ़े और मिल शक्कर का अधिकांश भाग विदेशी

मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात किया जाय।

देश में आज भी स्थिति यह है कि जन सधावारण को पोष्टिक दृष्टि से जितने मीठे की आवश्यकता होती है उतना नहीं मिल रहा है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति मीठे का उपभोग केवल २८ पौण्ड (१६ पौण्ड गुड तथा १२ पौण्ड चीनी) वार्षिक है, जबकि आस्ट्रेलिया में १४३, अल्जीरिया में १०६ तथा ब्रिटेन में ९६ पौण्ड है—डाक्टरों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को ४५६ पौण्ड मीठे की उपलब्धि वार्षिक रूप से होनी चाहिए। देश की अधिकांश गरीब जनता अपनी मीठे सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति गुड-खाण्डसारी से ही करती है।

उत्पादन लक्ष्य

गुड-खाण्डसारी मागलिक पदार्थ होने के साथ-साथ उत्तम खाद्य पदार्थ भी है। आहार की दृष्टि से चीनी की अपेक्षा गुड में पोष्टिक तत्व अधिक रहते हैं। गुड में ऐसे सभी खनिज तत्व होते हैं जोकि गन्ने के रस में मिलते हैं। चीनी में ऐसे तत्वों का अभाव रहता है। यही कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वास्थ्य और रोजगार दोनों की दृष्टि से इस उद्योग के विकास पर अत्यधिक जोर दिया था। सन् १९३२-३३ में टैरिफ बोर्ड ने खाण्डसारी उत्पादन का लक्ष्य ढाई लाख टन आका था। योजना आयोग ने द्वितीय योजना में सात लाख टन खाण्डसारी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था, किन्तु उसका उत्पादन मुश्किल से तीन लाख टन तक पहुँच पाया होगा। सरकार जैसे चीनी के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है, वैसे ही गुड और खाण्डसारी के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यदि इस उद्योग का वैज्ञानिक ढंग पर विकास किया जाय, तो निस्संदेह ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था रूपी वस्त्र में गरीबी और बेकारी का जो धब्बा लगा हुआ है वह काफी हद तक दूर हो सकता है। इसके अतिरिक्त चीनी की तरह गुड के निर्यात की भी काफी संभावना है।

कानपुर ९ जनवरी १९६४



पाठकों के विचार

खादी ग्रामोद्योग के दशम वार्षिकांक में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न विषयों पर कई अच्छे लेख हैं। खादी-विषयक तीन और अम्बर-विषयक एक लेख का जिक्र विशेष रूप से किया जा सकता है। ग्रामोद्योगों के विकास—जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारना है—में इस पत्रिका ने अपने जीवन के दौ वर्षों में जो योगदान दिया है, सम्पादकीय में उसका अच्छा सर्वेक्षण किया गया है। आपकी पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएँ।

शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल)

१ दिसम्बर १९६३

एस आर दास

उपकुलपति

विश्वभारती

*

*

*

खादी ग्रामोद्योग के दशम वार्षिकांक में खादी की भूमिका तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्य सम्बन्धी जानकारी-प्रधान और उद्देश्यपूर्ण आलोचनात्मक बहुमूल्य लेख हैं। लेखक-गण अपने क्षेत्र में काफी अनुभवी हैं, जिनके विचारों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

द्वितीय योजनावधि में सरकार ने खादी और ग्रामोद्योगों पर ८७ करोड़ से कुछ अधिक रुपये खर्च किये, जिनमें से अकेली खादी पर ६८ करोड़ ६८ लाख रुपये व्यय हुए। तृतीय योजनावधि के लिए ९२ करोड़ रुपये का प्रावधान है।

निवेश की तुलना में हो सकता है कि इस धन-राशि

से कोई खास आर्थिक लाभ न हो। लेकिन जब तक व्यापक उत्पादक रोजगारी और आय का समाजवादी वितरण पूर्णता पर नहीं पहुँच जाता, तब तक ग्रामीण दस्तकारियों को अपने विभिन्न सीमा तक के यात्रीकरण—तकली और चरखा भी यत्र ही हैं—के साथ और बिजली का अधिकाधिक इस्तेमाल करते हुए ग्रामीणों के धंधे और आय में पूरक बना ही रहना है। जिम्मेदार सरकार और सामाजिक रूप से चेतन नागरिक को इन दस्तकारियों तथा इन पर निर्भर करनेवाले लाखों लोगों को सहारा देना ही है।

तथापि, हमें हमेशा यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए—जैसा कि गांधीजी ने रखा—कि खादी तथा अन्य गारीरिक मेहनतवाले कार्य लक्ष्य तक पहुँचने के साधन भर हैं और लक्ष्य है बेरोजगारी व गरीबी को दूर करना। कृषि के लिए साल भर जल पूर्ति और कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए सस्ती बिजली देने से पूर्ण रोजगारी और पर्याप्त आय दोनों ही सुनिश्चित होते हैं। एक एकड़ सिंचित भूमि चार व्यक्तियों को साल भर काम देती है और एक किलोवाट बिजली कई लोगों को धंधे में लगावेगी। अतः हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम आज की आवश्यकता को हमेशा का लक्ष्य न बना ले। जैसा कि श्री अरुण चन्द्र गुहा ने अपने लेख में कहा है, “(खादी और ग्रामोद्योग) कमीशन को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि बड़ी इकाइयों की शक्ति का कुटीरोद्योगों में इस्तेमाल करने से वे दूषित हो सकते

है। कमीशन इस सवाल पर विचार कर सकता है कि शक्ति चालित करघों के साथ शक्ति में चलाये जानेवाले कताई यंत्र को कुटींग उद्योग का आधार माना जा सकता है या नहीं।”

बिजली न सिर्फ रोजगारी फैलाने और उत्पादन बढ़ाने का हल प्रदान करती है, बल्कि समझ-बूझ और सोच-विचार कर उसकी योजना बनाने से वह गाँववालों को खुशी-खुशी गाँव में रख भी सकती है। इसका हितावह परिणाम तुरन्त ही स्पष्ट हो जायेगा। शहरों में उद्योगों के जमाव से लोगों का जो अवाछिन जमाव हो जाता है, गद्दी बस्तियाँ तथा तकलीफें बढ़ जाती हैं, वे सब सदा के लिए दूर हो जायेगी। अतः सुदूर गाँवों तक बिजली के वितरण तथा धन और अवकाश के सम वितरण से गांधीजी के सपनों का गाँव तैयार होना चाहिए, जोकि सचमुच उनके सपनों का भारत है।

नयी दिल्ली

के एल राव

१९ दिसम्बर १९६३

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री

मैंने विशेषांक बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा। कमीशन के नये अध्यक्ष ने अपने लेख में ग्रामोद्योगों की भूमिका के एक विशेष गुण साथ ही (“साथ वे प्रविधि तथा उत्पादन में व्यवहृत उपकरणों और तौर-तरीकों में सुधार करने के अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। धीरे-धीरे सुस्थिर गति में नव अभिक्रम का निर्माण करने तथा सृजनशीलता को बढ़ावा देने में भी वे सहायक होते हैं।”) की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कमीशन ग्रामोद्योग की सुस्थिर प्रगति में अधिकाधिक सहायक हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे समान अन्य पाठक भी इस प्रकार उन्नति करने के सन्दर्भ में आपकी अमूल्य पत्रिका का पठन करेंगे। अपने उच्च कोटि के विशेषांक के लिए क्या मैं आपको बधाई दे सकता हूँ।

बम्बई

दत्तात्रेय गोपाल कर्वे

१४ अक्तूबर १९६३

डिप्टी गवर्नर

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

बर्तानिया पहले से ही उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार के प्रति कृत-संकल्प है। आम तौर पर यह आलोचना होती है कि विस्तार का पैमाना बहुत छोटा है। आगामी बीस वर्ष का हमें पता है कि छात्र कहाँ से आयेंगे और यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि उनके स्नातक बनने पर यहाँ अथवा अन्यत्र उन्हें काम मिल जायेगा अर्थात् उनके लिए काम मौजूद है। हम यह भी जानते हैं कि बढ़ती हुई सख्या की आवास-व्यवस्था के लिए भवन-निर्माण कैसे किया जाय, लेकिन हम यह नहीं जानते कि शिक्षक कहाँ से आयेंगे।

—सर एरिक अँशबी ‘इनवेस्टमेंट इन
मैन’, न्यू साइन्टिस्ट, लन्दन।

दशम वर्ष • मार्च १९६४ • षष्ठम अंक



पृष्ठ

सामान्य उत्पादन कार्यक्रम	-उत्तरंगराय न. ठेबूर	३९५
परिगणित जातियो व परिगणित जन-जातियो की अवस्था मे सुधार	-वैकुण्ठ ल. मेहता	३९८
खादी आन्दोलन मे क्रांतिकारी परिवर्तन	-अनन्त वासुदेव सहस्रबुद्धे	४०१
मधुमक्खी-पालन उद्योग की समस्याएं	-राम सुमंग सिंह	४०४
पचाव की अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएं	-विक्टर सा. डी'सोजा	४०८
भारत मे मधुमक्खी-पालन	-सुभाष चन्द्र सरकार	४१७
मधुमक्खी-पालन उद्योग समीक्षा	-सीताराम गं. शेण्डे	४२१
मौन-पालन मे अनुसंधान	-गोविन्द बालकृष्ण देवडीकर	४२३
मधुमक्खिया और परागाधान	-हरिहरन विश्वनाथन	४२६
आधुनिक मधुमक्खी-पालन	-जे. राजग्या	४२९
खादी आन्दोलन का बुनियादी विचार	-कमलेश्वरानन्द पाण्डेय	४३२
पूर्वी उत्तर प्रदेश की अविकसित अर्थ-व्यवस्था	-इम्तफा हुसैन	४३५
ग्रामीण महाराष्ट्र मे सहकार की प्रगति	-प्रभाकर नाडकर्णी	४४१
तेल पेराई मे सुधार	-त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्ति	४४९
गांधी सेवक समाज	-वैकुण्ठ ल मेहता	४५४

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोदय', इर्ला, बम्बई-५६ से मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थ शास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। टेलिफोन नं ५७१३२९।

इस पत्र मे प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ नये पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए असिस्टेण्ट एकाउण्ट्स ऑफिसर (कैश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६।

इस अंक के लेखक

उछरगराय नवलशकर डेबर

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष ।

वैकुण्ठ लल्लूभाई मेहता

—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।

अनन्त बासुदेव सहस्रबुद्धे

—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।

राम सुभग सिंह

—केन्द्रीय कृषि मंत्री ।

विक्टर सालवादोर डी'सोजा

—चण्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष ।

सुभाष चन्द्र सरकार

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित 'खादी ग्रामोद्योग' तथा 'जागृति' के सम्पादक ।

सीताराम गगाधर शेषडे

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में मधुमक्खी-पालन उद्योग निर्देशक ।

गोविन्द बालकृष्ण देवडीकर

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पूना स्थित केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था में मधुमक्खी-पालन के अवैतनिक वैज्ञानिक सलाहकार ।

हरिहरन विद्वनाथन

—मद्रास राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के मधुमक्खी-पालन विकास अधिकारी ।

जे राजय्या

—मार्तण्डम (मद्रास) स्थित यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के कार्यभारी (मधुमक्खी-पालन) सचिव ।

कमलेश्वरानन्द पाण्डेय

—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य, दिल्ली ।

इस्तफा हुसैन

—उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्व ससदीय सचिव, गोरखपुर ।

प्रभाकर शंकर नाडकर्णी

—महाराष्ट्र के पूना स्थित संयुक्त औद्योगिक सहकार पंजीयक ।

त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्ति

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के ग्रामीण तेल उद्योग विकास अधिकारी ।

सामान्य उत्पादन कार्यक्रम

उछरगराय न. देबर

भारतीय आर्थिक विकास का प्रश्न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का ही नहीं, बल्कि एकांगी अभिवृद्धि का भी है। पांच करोड़ हरिजनों को जानबूझ कर, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से अलग रखा गया है। सामाजिक और आर्थिक अस्पृश्यता ने उनके मानसिक धरातल पर हीन ग्रथियो और सशय की अमिट छाप छोड़ रखी है। हम लोग इस वास्तविक तथ्य को नजरदाज नहीं कर सकते कि हम एक ऐसे समुदाय में काम कर रहे हैं, जिसमें सामुदायिक जागरण और अभिवृद्धि की अवस्थाएँ तथा स्तर भिन्न-भिन्न हैं। जब तक व्यक्ति और समष्टि यानी दोनों स्तरों पर इतनी चेतना का सृजन न हो जाय कि प्रत्येक व्यक्ति भलिभाति अपना कर्तव्य समझने लगे, तब तक आम जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकना बहुत ही मुश्किल है।

सामान्य उत्पादन कार्यक्रम का उद्देश्य था ऐसी व्यवस्था करना कि लघु उद्योग अपने लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने में समर्थ हो सके। इस लक्ष्य-पूर्ति के प्रश्न पर विचार करने के लिए हमें तीन स्थितियों पर गौर करना होगा— लक्ष्यो तक पहुँचने में कहाँ तक सफलता मिली, साथ-साथ उन लक्ष्यो की पूर्ति के लिए सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से जो उपाय किये गये वे पर्याप्त थे या नहीं और उन उपायो तथा क्षेत्र की वास्तविक अवस्थाओ के बीच कोई अंतराल तो नहीं था। कुछ आलोचको ने खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम की आलोचना इस कल्पना के आधार पर की है कि प्रस्तावित उपाय पर्याप्त थे तथा क्षेत्रीय स्तर की तत्कालीन अवस्था एवं किये गये उपायो के बीच कोई अंतराल नहीं था। उनका अन्ततः खयाल ऐसा है कि चूँकि लक्ष्यो की पूर्ति नहीं हो सकी है, इसलिए कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया जाय, क्योंकि समुदाय की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए न तो वह कुछ दे रहा है और न कुछ दे सकने की सम्भावना ही है।

विचारधारा में अन्तर

स्थिति का नक्श कुछ इस प्रकार है, जिसका चित्रण मैं यहाँ कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ इसमें मैं स्पष्ट हूँ।

मैं महसूस करता हूँ कि किये गये उपाय सिर्फ अपर्याप्त ही नहीं थे, बल्कि हमारी विचारधारा में एक ऐसा अन्तराल रह गया है जिसके परिणाम हम में से अनेक लोगो को पसन्द नहीं है। हमारी विचारधारा का यह अंतराल इतना व्यापक है कि उसके परिणाम-स्वरूप हम अनेक क्षेत्रों में लक्ष्य तक नहीं पहुँच सके और या तो खुद कार्यक्रम को ही दोषी हराने का रुख अख्तियार कर रहे हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, या फिर ऐसा बलि का बकरा खोजते फिरते हैं जो आसानी से मिल जाय।

योजना आयोग के समक्ष पेश किये गये अपने 'नोटो' में मैंने इस प्रश्न की व्याख्या की है और न्यूनतम आय तथा अर्थ-व्यवस्था के आम विकास, दोनों को लिया है। संक्षेप में मेरी व्याख्या इस प्रकार है हम लोग एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हमारे देश की आम जनता प्रत्यक्ष रूप से तब तक स्वीकार नहीं कर सकती, जब तक उसके अन्दर इतनी चेतना न आ जाय कि वह उसे अंतर्ग्रहण कर सके। ग्रामीण उद्योगो में सहकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डा सुन्दरम* ने भी यही बात कही है। उनका कहना

* जो डु सुन्दरम • 'कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्रैम', कॉमर्स, बम्बई, ७ और १४ दिसम्बर १९६३।

है, "ग्रामीण औद्योगीकरण में सहकारिता की भूमिका पर बारबार कुछ ऐसा जोर दिया जा रहा है, मानो व्यक्ति और सामाजिक चेतना एवं सामाजिक दायित्व तथा जागरण की समस्त समस्याएँ हल कर ली गयी।" जब तक व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर इतनी चेतना न आ जाये कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाय, तब तक आम जनता से सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकना मुश्किल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकार आन्दोलन को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे इसी बुनियादी कारण से उत्पन्न होती हैं। मेरा खयाल है कि इस क्षेत्र में हम विनोबाजी और गांधीजी के उपदेशों से काफी लाभ उठा सकते हैं।

निराधार

ग्रामीण विकास की समस्या पर जितना ही विचार करता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर और गहन विचार करने की आवश्यकता है। प्रश्न सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन का ही नहीं है, बल्कि एक पक्षीय अभिवृद्धि का भी है। इस एक पक्षीय पहलू का निराकरण जब तक नहीं हो जाता, पिछड़ापन भी आसानी से नहीं जा सकेगा। यह तो कुछ ऐसा है कि ठोस बुनियाद की कल्पना के आधार पर हम अट्टालिका खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दरअसल, स्थिति यह है कि बुनियाद में पत्थर की कौन कहे, बालू की भित्ति भी नहीं है।

पाच करोड़ हरिजनो को, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जानबूझ कर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से अलग रखा गया है। वे सब तरह के घटिया काम करते हैं, किन्तु उनके साथ अनिवार्य रूप से सामाजिक और आर्थिक च्युति के व्यवहारों ने उनके मानसिक धरातल पर हीन भावनाओं एवं आत्म सशय की अमिट छाप छोड़ दी है। इसी तरह करीब आठ करोड़ आदिवासी पूरे अलगाव में रहते हैं। वे अब तक यह भी नहीं जानते कि 'योजना' नामक दस्तावेज में क्या है। उनकी चेतना का स्तर अब भी यही है कि अपने दलीय विकास पर

सोचने की बजाय वे अब तक सिर्फ अपने ही आराम की बात सोचते हैं। भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा अंग सिर्फ मवेशियों की नस्ल-सुधार का काम करता है। वे अधिकतर खानाबदोश होते हैं। इसी तरह और भी बहुत-से सामाजिक दल हैं, जो उतने ही या उनसे अधिक पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण समुदाय शब्द से बोध होता है एक पंचमेल समाज का, जिसकी जटिल आंतरिक समस्याएँ 'यह करो', 'वह न करो' की आज्ञाओं या वर्जन की आज्ञाओं से और भी जटिल बन गयी हैं। इस गड्ढमड्ड सामाजार्थिक मकड़ी के जाले को काटना निहायत जरूरी है। पहले हमें इतना स्पष्ट नहीं मालूम था। अतः अगर हाथ करघे या अम्बर चरखे के कार्यों में कोई दिक्कत हुई तो वह कार्यक्रम के स्वरूप में किसी अतिनिहित भूल की वजह से नहीं। बुनियादी भूल तो हमारी इस कल्पना में है कि जिस किसी वस्तु हम कार्यक्रम को भारतीय समाज के दरवाजे पर ले जायेंगे, वह उसके वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलू को तह दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है। असल कठिनाई तो यही है कि भारतीय आम जनता और किसी प्रौद्योगिकीय ठोस कार्यक्रम के प्रति उसकी स्वीकृति के बीच मानसिक संकोच की कुण्ठा व्याप्त है, जो सिमेंट की दिवाल की तरह खड़ी है। आम जनता आज भी अपनी अवस्थाएँ और शर्तों के मुताबिक ही अपने विकास की बात सोचती है, ताकि उसका वर्तमान सामाजिक ताना-बाना अक्षुण्ण बना रहे।

जनता और विकास कार्य

इस सदर्थ में १८८५ से १९१५ के बीच राजनीतिक नेताओं के प्रयासों की याद करना शिक्षाप्रद होगा। उन लोगों ने शौर्यपूर्ण वार्ताओं के जरिये स्वतंत्रता के प्रश्न पर भारतीय जनता की उदासीनता के जाल को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश की। वे पश्चिमी दुनिया के घाघ राजनीतिज्ञों तथा अर्थ-शास्त्रियों की भाषा में बोलते थे। यह यथा योग्य भी था। किन्तु जनता की अवस्था यह थी कि पश्चिमी दुनिया के चेतना स्तर तक वह नहीं पहुँच पायी थी और भारतीय राजनीतिक

नेताओं की भाषा साधारण भारतीय जनता की पहुँच के बाहर थी। गांधीजी ही एकमात्र नेता थे, जिन्होंने सर्व प्रथम राजनीतिक और आर्थिक विषयों की ओर उदासीन जनता का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा कर सकने में वे इसलिए सफल हुए कि वे ऐसी भाषा बोलते थे जो साधारण जनता की समझ में आये। बद्धिस्मृती से, वह भाषा, जिसमें आम जनता समझ सकती थी, बौद्धिक वर्ग के लिए दुर्बोध्य थी। आज हम विकास के क्षेत्र में वही अवस्था देखते हैं। हम में से अधिकांश ऐसी भाषा बोलते हैं, जो जनता मुश्किल से समझ सकती है, किन्तु हम विश्वास किये बैठे हैं कि चूँकि हम लोग उसके लिए स्कूलों और अस्पतालों की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए वह हमारे प्रयासों में अवश्य साथ देगी।

हमने जो भी सुविधाएँ प्रदान की हैं, भारतीय जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। किन्तु ये सुविधाएँ उन लोगों को राष्ट्रीय विकास के प्रयासों की प्रमुख धारा की ओर आकर्षित कर सकने में सफल नहीं हो पायी हैं, क्योंकि हम उस तार को झकृत नहीं कर पाये हैं जो उन्हें स्वयमेव धारा की ओर खींच ले। हमारी समझदारी का यह फर्क, दुर्भाग्यवश, अनेक अन्य विरोधों को सामने ला रहा है।

वास्तविकता और समझ

खादी और हाथ करघा कार्यक्रम को उठा देना कठिन नहीं है, किन्तु गावों की जनता को लाभकारी धंधा प्रदान करने के लिए उनके स्थान पर दूसरे धंधों की व्यवस्था कर सकना आसान न होगा। बड़े पैमाने के उद्योगों की कार्यप्रणाली पर अगर मुझे कोई 'नोट' लिखना हो तो, पश्चिमी अर्थशास्त्रियों को यह दिखा सकने में मैं शायद ज्यादा सफल होता कि उस क्षेत्र में कितनी अक्षमता है और देश को उसे बनाये रखने में कितना भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है। यह अक्षमता निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में मौजूद है।

भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को नजरन्दाज करना मुश्किल है— हमें एक ऐसे समुदाय के बीच काम

करना पड़ रहा है जो सामाजिक चेतना और अभिवृद्धि के विभिन्न स्तरों और अवस्थाओं से होकर गुजर रहा है। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि ये विभिन्नताएँ खुद-ब-खुद एकता में बदल जायेगी और हमारी योजनाओं तथा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में सहाय्य दे दे लगेगी। इस बात का खयाल रखना बहुत जरूरी है कि इन अवस्थाओं को अनुकूल बनाने तथा अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उनके उद्देश्यात्मक उपयोग के लिए घोर प्रयासों की आवश्यकता है। इस सर्वांगीण महत्वपूर्ण तथ्य को स्वीकार कर लेने के बाद अपने कार्यक्रम को क्षेत्रीय अवस्थाओं के अनुकूल वैज्ञानिक मोड़ देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वास्तविकता और अपनी समझदारी के बीच के अन्तराल को पाटने की तात्कालिक समस्या की ओर से अगर हम नें मुँह मोड़ा तो उसका क्रूरता पूर्ण परिणाम होगा तानाशाही का उदय। आम खयाल है कि दक्ष इकाइयों जब से काम शुरू करेगी, बचत होने लगेगी और उस बचत से हम अपनी अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार की विचारधारा में बड़ी भ्रांति है। हमारे सपने की इन दक्ष इकाइयों और क्षेत्रीय स्तर की वास्तविकताओं के बीच दिवास्वप्न है, जिसकी वजह से हम काफी भोग चुके हैं। अब यह बेहतर होगा कि कार्यक्रम में हम जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल मोड़ लायें और उससे कहे कि लक्ष्य तक पहुँचने में उसे भी अपनी जिम्मेवारी का निश्चित अंश पूरा करना है।

अपने विकास के स्तर के अनुकूल जनता जिस भाषा को समझती है, वह रोजी और रोटी की भाषा है तथा वह भी अपनी दक्षता व चेतना के अनुरूप। इन्हीं कारणों से मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक आधारहीन जनता को उसमें शामिल करने का सर्वोत्तम तरीका है— कृषि, पशुपालन तथा ग्रामोद्योगों के लिए केन्द्रित प्रयास करना। हम जनता की पहुँच और समझ के परे के सामान्य उत्पादन कार्यक्रम को भूल जाय और ऐसे कार्यक्रम की सोचें, जो उसकी समझ और पहुँच के अन्दर हों।

परिगणित जातियों व परिगणित जन-जातियों की अवस्था में सुधार

वैकुण्ठ ल. मेहता

परिगणित जातियों और परिगणित जन-जातियों की आबादी देश की कुल जन संख्या की २१ प्रतिशत है। उनके लिए ग्रामीण औद्योगीकरण के एक प्राणवान कार्यक्रम का होना अपरिहार्य है।

अब यह अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि यदि हमें अपने देश से गरीबी को निर्मूल करना है तो साल के बड़े भाग में बेकार अथवा अर्ध-बेकार रहनेवाले लाखों-करोड़ों लोगों के लिए काम की व्यवस्था करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी ही चाहिए। हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों के अलावा यह जड़-वस्था इस कारण भी है कि अर्ध-बेकारी से बुरी तरह पीड़ित व्यक्ति बहुत बड़ी तादाद में गांवों में रहते हैं, यह कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कर्मियों की औसत आय में असमानताएं हैं तथा गांवों में रोजगारी प्रदान करनेवाले मुख्य साधन—भूमि—पर आबादी का अधिक दबाव है। अतः न्यून आय वर्ग में शहरी आबादी से अधिक अनुपात ग्रामीण आबादी का है। इन वर्गों में भी अधिकांश वे लोग मिलेंगे, जो कि जन-जातियों तथा परिगणित जातियों के हैं। इसी कारण ग्राम्य समाज के कमजोर वर्गों की अवस्था का अध्ययन करनेवाले दल ने यह विचार प्रकट किया कि जन-जातियों अथवा परिगणित जातियों के सभी लोग इस श्रेणी में आते हैं।

अध्ययन दल तथा परिगणित क्षेत्र और परिगणित जन-जाति आयोग, दोनों का ही यह मत था कि ग्राम्य समाज के इन कमजोर वर्गों की गरीबी कम करने के लिए प्रथम उपाय है उनका आर्थिक विकास। आयोग द्वारा प्रस्तावित इस तरह के विकास का उद्देश्य होना चाहिए साल में ३०० दिन काम चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगारी सुनिश्चित करना। अध्ययन दल का भी

करीब-करीब यही मत था। अतः यह उचित ही था कि योजना आयोग ने इस वर्ष जनवरी माह के अंत में 'परिगणित जाति और परिगणित जन-जातियों को रोजगारी' विषयक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता योजना आयोग के सदस्य डाक्टर विजयेन्द्र कस्तूरी रंग वरदराज राव ने की।

ग्रामीण जड़-वस्था दूर करना

अग्रतः अध्यक्षीय भाषण में डा. राव ने कहा कि चूंकि परिगणित जाति के ६ करोड़ ४५ लाख लोग और परिगणित जन-जातियों के २ करोड़ ९१ लाख ८० हजार लोग मिल कर देश की आबादी के २१ प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं, अतः आबादी के इतने बड़े भाग की रोजगारी अवस्था में सुधार होने से सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ने ही वाला है। समस्या मुख्यतः ग्रामीण जड़ता को दूर करने की है, वह इसी तथ्य से स्पष्ट है कि परिगणित जातियों के सिर्फ १०.७ प्रतिशत और परिगणित जन-जातियों के सिर्फ २.६ प्रतिशत लोग ही शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि आम आबादी का १७.८ प्रतिशत भाग शहरी में रहता है।

इन वर्गों की गंभीर अवस्था का पता इस तथ्य से भी लगता है कि कृषि पर निर्भर करनेवाले कर्मियों की संख्या परिगणित जन-जातियों में ८७.८८ प्रतिशत है और परिगणित जातियों में ७२.२ प्रतिशत। परिगणित जातियों के प्रातिशब्द में से करीब आधे अर्थात् ३४.६६ प्रतिशत तो कृषि मजदूर हैं, जबकि श्रमिक शक्ति में

सभी वर्ग के कृषि मजदूरो का प्रातिशत्य १७ है। सन् १९५१ और १९६१ के बीच कृषि मजदूरो की संख्या २ करोड ७५ लाख से बढ़ कर ३ करोड १५ लाख हो गयी, और यह इस बात की परिचायक है कि भूमि पर आबादी का बोझ बढ़ा है, क्योंकि इस अवधि में खेती के अन्तर्गत जो भूमि है उसमें इस अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है। दबाव बढ़ने से मुख्यतः परिगणित जातियो, परिगणित जन-जातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो सर्वेक्षण किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि देश के अधिकांश भागों में कृषि-मजदूरी इन्हीं पिछड़े वर्गों के लोगो द्वारा की जाती है। फिर, परिस्थितियों के दबाव के कारण परिगणित जन-जातियो और परिगणित जातियो में सम्पूर्ण आबादी की बनिस्बत कर्मियों का अनुपात अधिक है और इन तीनों का प्रातिशत्य क्रमशः ५६.६५, ४७.०७, और ४२.४८ है।

बाधाएँ

परिगणित क्षेत्र और परिगणित जन-जाति आयोग के प्रतिवेदन तथा हाल की गोष्ठी में प्रस्तुत सामग्री में भी जन-सेवाओं तथा अन्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये रोजगारी के अवसर उपलब्ध करने पर विशेष जोर दिया गया है। समस्या की भीषणता को देखते हुए इस तरह की रोजगारी का परिमाण शायद ही इतना हो कि वह काम की वृहत माँग की पूर्ति कर सके। फिर, इस तरह की रोजगारी की राह में कुछ बाधाएँ भी हैं। सर्व प्रथम, आम आबादी की तुलना में इनमें निरक्षरता प्रातिशत्य बहुत अधिक है—परिगणित जन-जातियो में ९१.५२ प्रति शत, परिगणित जातियो में ९०.०५ प्रति शत और आम आबादी में ७२.९८ प्रति शत। द्वितीय, जैसी कि अपेक्षा की जा सकती है, काम दिलाऊ दफ्तरों की बहियों में परिगणित जातियो और जन-जातियो के जितने लोगो का नाम दर्ज है उनमें से अधिकांश 'अकुशल कर्मचारी श्रेणी' में आते हैं और उनका प्रातिशत्य परिगणित जातियो के लिए ६८ तथा परिगणित जन-

जातियो के लिए ७२ है। उनका शैक्षणिक स्तर उन्नत हो सके तथा वे इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकल धंधों में प्रशिक्षण ले सके अथवा वे अपने ही परम्परागत या अन्य धंधों में कुशलता प्राप्त कर सके, इसमें कुछ समय लगेगा। गोष्ठी में प्रस्तुत निबन्धों से सामान्य अनुभव यही होता है कि जिन वर्गों को छात्रवृत्तियाँ प्राप्त हैं, उन्होंने सामान्य शिक्षा का क्षेत्र चुना है और उद्योग तथा तकनीकल प्रशिक्षण के लिए बहुत कम उत्साह दिखाया है। जैसा कि डा. राव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सुझाया है, हो सकता है कि विशेष उत्प्रेरणा देना सहायक हो, परन्तु इस बीच इस तथ्य को तो स्वीकार करना ही होगा कि इन वर्गों में उद्योगों में कुशल दस्तकारों के रूप में रोजगार पानेवालों की संख्या नगण्य ही है।

खेती में रोजगारी

चूँकि इन वर्गों के अधिकांश लोग अपनी जीविका मुख्यतः खेती से ही प्राप्त करते हैं, अतः प्रथम दृष्टि में अवस्था सुधारने के लिए जो उपाय नजर आता है वह है हमारे राष्ट्रीय उद्योगों में रोजगारी की सम्भावना बढ़ाना। तथापि, इस क्षेत्र में भूमि पर वर्तमान भार और भूमि-बन्दोबस्त के लिए बड़े क्षेत्र की अनुपलब्धि के अतिरिक्त कुछ अन्य सीमाएँ भी हैं। तथापि, जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध है प्रत्यक्षतः वहाँ प्रथम कार्य तो इन वर्गों के लोगो को बसाना और फिर उन्हें आर्थिक तथा तकनीकल सहायता देना होना चाहिए। परिगणित जातियो के २ करोड ४० लाख लोगो को खेतिहर बताया गया है, जिनमें से अधिकांश के पास खेत इतने छोटे-छोटे हैं कि उनकी अवस्था खेतिहर मजदूरो से अच्छी नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, कृषि मजदूरी में लगे परिगणित जातियो के लोगो का अनुपात आम आबादी के अनुपात से अधिक है। अतः खेती के लिए भूमि मिलने पर कृषि कार्य करनेवाले दोनों प्रकार के कर्मिलाभान्वित हो सकते हैं। यदि बन्दोबस्त के लिए भूमि मिले तो परिगणित जन-जातियो को भी लाभ होगा। जैसा कि डा. राव ने अपने भाषण में बताया,

अभी परिगणित जातियों के जिन दो करोड़ व्यक्तियों को खेतिहर दिखाया गया है, उनकी अवस्था परिगणित जन-जातियों के खेतिहरो से कोई अच्छी नहीं है।

जैसा कि परिगणित क्षेत्र और परिगणित जन-जाति आयोग ने जोर दे कर कहा है कि रोजगारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजन व्यापक होना चाहिए। उसमें कृषि, वन, पशु-पालन तथा कुटीर और लघु उद्योगों का समग्र विकास शामिल होना चाहिए। आर्थिक विकास के इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए उक्त आयोग ने व्यापक सिफारिशें की हैं, जिनका राष्ट्रीय योजना के अग स्वरूप जोरदार ढंग से पालन होना चाहिए। उदाहरणार्थ कृषि क्षेत्र में भूमि बन्दोबस्त के अलावा भ-सुरक्षण के उपायों का प्रसार, सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था और उन्नत अथवा सघन खेती के तरीकों का समावेश करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

वन्य कार्य

आयोग ने सिफारिश की है कि जंगलों के जरिये काम के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम में उनके सुरक्षण से उपयोग तक के हर स्तर पर आदिवासियों के लिए रोजगारी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसने आप्रह किया है कि वन विभाग को इन आदिवासी समुदायों को भागीदार समझना चाहिए और स्थानीय आदिवासियों के हित में चलाये जानेवाले प्रशोधन तथा अन्य उद्योगों के लिए वनों की खोज और उपयोग करने देना चाहिए। आयोग के अनुसार पशु-पालन को सक्रिय प्रोत्साहन देना चाहिए— खास कर उन क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी भवेशियों को हल जोतने तथा अन्य प्रकार की खीचन-शक्ति प्राप्त करने अथवा दूध-दूहने के काम में लाते हैं।

तथापि, आयोग इस सम्बन्ध में आश्वत हो गया था कि “कृषि की न्यून क्षमता के कारण आदिवासी क्षेत्रों में निराश्रिता और अव-सामान्य जीवन-स्तर” की जो समस्या है, वह मुख्यतः ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का

विकास कर ही हल की जा सकती है। इन उद्योगों के विकास से आदिवासियों की सर्जनात्मक शक्ति का उपयोग और विकास करना, उन्हें लाभदायक रोजगारी उपलब्ध करना और कच्चे माल को प्रशोधित माल में बदलने के अवसर प्रदान करना पूर्णतः सम्भव है। ये तीनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, किन्तु परिगणित जातियों और परिगणित जन-जातियों में रोजगारी सबबी गोष्ठी के सन्दर्भ में प्रथम यानी रोजगारी सम्बन्धी बात प्रधान है।

परिगणित जन-जातियों के सम्बन्ध में जो बात प्रयुक्त होती है, वही चन्द सशोधनों के साथ परिगणित जातियों के लिए भी लागू होती है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में ये भी समाज के कमजोर वर्गों में आते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में वे पिछड़ी हुई हैं, अधिकांश स्थानों में वे बाकी समाज से सामाजिक रूप में अलग-थलग हैं, और वे तकनीकल प्रशिक्षण अथवा कुशलता प्राप्त करने की सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप वे अपने परम्परागत उद्योगों में समजन नहीं कर पाते और न ही आर्थिक साधन-स्रोतों तथा तकनीकल मार्गदर्शन की कमी होने के कारण वे अपने सरजामों और तकनीकों में सुधार करने की अवस्था में हैं, जैसे कि रेशा उद्योग, शक्छेदन, चर्मशोधन और चमड़ा काम में। इन परम्परागत उद्योगों को, स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल और अन्य स्रोतों के पूर्ण उपयोग के आधार पर, पुनरुज्जीविन करने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम बनाने से न सिर्फ रोजगारी की सम्भावना बढ़ेगी, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक दर्जों में स्वागत योग्य परिवर्तन भी होगा। अतः जहाँ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु ग्रामीण औद्योगीकरण का प्राणवान कार्यक्रम अत्यावश्यक है, वहाँ परिगणित जातियों और परिगणित जन-जातियों के हित में—जोकि हमारे समाज के सर्वाधिक दलित और अधिकारविहीन वर्गों में हैं—तो तुरन्त वैसा कार्यक्रम चलाना परमावश्यक है।

बम्बई • २८ फरवरी १९६४

खादी आन्दोलन में क्रांतिकारी परिवर्तन

अनन्त वासुदेव सहस्रबुद्धे

यदि खादी की दुनाई उपदान नामक नयी योजना के कार्यान्वय के फलस्वरूप गाँववाले खादी उद्योग के विकास की जिम्मेदारी लेने को उत्साहित हों तो यह एक उल्लेखनीय सफलता मानी जायगी। वर्तमान कार्य को ही नया रूप देने से सहज होगा नये क्षेत्रों में नयी पद्धति से कार्य का संगठन करना, और इतना ही नहीं, इससे देश भर में ग्रामाभिमुख खादी कार्य के विकास का पथ भी प्रशस्त होगा।

खादी के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। भविष्य में खादी कार्य किस तरह से चले, इस दृष्टि से गांधीजी ने १९४५ में देश के सामने कुछ विचार रखे थे, उन सब को सकलित करके 'चरखा सव का नवसंस्करण' नाम से प्रकाशित किया गया। गांधीजी का कहना था कि चरखा सव देश के लिए बना था, और अब उसे गाँव-गाँव में वितरित हो जाना चाहिए। गाँववाले अपने लिए सूत काते, खुद के लिए कपड़ा बनाये और गाँव की आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद माल को बाजार में बेच दे। खादी को ग्रामाभिमुख बनाने, ग्राम स्वराज्य की नींव खादी के द्वारा डालने और एक अहिंसक समाज रचना की तरफ चरखे के द्वारा देश को ले जाने का विचार १९४५ में ही गांधीजी ने रखा था।

आज उस बात को १८ साल हो गये हैं। इस अवधि में हम लोगो ने पुराने ढंग से ही खादी काम को चलाया। अखिल भारत चरखा सव का काम देश में हजार-दो हजार संस्थाओं में विभाजित हुआ, लेकिन तरीका वही रहा। कस्बे को रोजी की आवश्यकता है, अतः वह कातती है और उसकी खादी बनाने की जिम्मेदारी संस्थाओं की रहती है। इससे न गाँव में संगठन खड़ा हुआ है और न गाँव के आर्थिक विकास की नींव ही डाली जा सकती है। आचार्य विनोबा भावे के मार्गदर्शन में फिर से इसके बारे में गत वर्ष से सोचा जा रहा था और अतः रायपुर में खादी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन

हुआ तथा उसमें यह तय किया गया कि खादी को ग्रामाभिमुख बनाने का नया तरीका अपनाया जाय।

खादी की तरफ देखने के दो दृष्टिकोण आज हमारे सामने आते हैं। गांधीजी मानते थे कि खादी जीवन की एक पद्धति (Way of Life) है। हर घर में जैसे भोजन बनता है वैसे ही कताई का काम चले और उस पर व्यापारिक अर्थशास्त्र के सारे सिद्धान्त लागू नहीं किये जायें। इस दृष्टि से यदि सोचा जाय तो हमारे आज के काम में बहुत-सी खामिया देखने में आती हैं। देश के हर एक गाँव में खादी का कार्यक्रम गाँववालों को चाहिए या नहीं, यदि आज इस पर मत लिये जाय तो बहुमत हमारे खिलाफ ही जायेगा। इसका अर्थ है कि हम लोगो ने भी अभी तक खादी के अनकूल वायुमण्डल नहीं बनाया है। आज भी गाँववालों को खादी गाँव के आर्थिक विकास की बुनियाद नहीं लगती।

आर्थिक ढांचा बदलनेवाली नहीं

खादी-ग्रामोद्योगों के आधार पर ग्रामीण विभाग की आर्थिक रचना हो, यह विचार न आज जनता मानती है और न सरकार की तरफ से उसके लिए कोई खास आग्रह है। इसलिए आज की हमारी खादी गाँव का आर्थिक ढांचा बदलनेवाली नहीं रही। आज खादी के द्वारा एक तरह से राहत का काम होता है, कुछ बेकारी दूर करने का काम भी उससे हो जाता है।

देश के कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि खादी के द्वारा अर्ध-बेकारो और गुप्त-बेकारो को काम दिया जा सकेगा तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन का यही उद्देश्य होना चाहिए। बेकारी निवारण का काम खादी के जरिये नहीं हो सकेगा। शायद खादी जमात इससे सहमत नहीं होगी, लेकिन आज देश की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है और जिन अर्थशास्त्रियों के मत से आज की योजनाएँ बनती हैं, उनकी ऐसी ही राय रही है। खादी याने खेती का एक सहकारी उद्योग, लेकिन बेकारो को पूरी रोजी देने का काम उससे नहीं होनेवाला है।

ग्रामाभिमुख

खादी की तरफ देखने का दूसरा दृष्टिबिन्दु है—खादी को धीरे-धीरे औजारो तथा तकनालाजी में सुधार करके मिलो की प्रतिस्पर्धा में भी कुछ हद तक खड़ी रहना चाहिए और कपड़ा उद्योग देश में विकेन्द्रित ढंग से चले, ऐसी रचना करनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि खादी मिलो से कभी भी स्पर्धा नहीं कर सकती। लेकिन इस तरह की तकनीक अपनायी जा सकती है, जिससे खादी व मिल के कपड़े में १०-१५ प्रति शत से ज्यादा अन्तर नहीं रहे। उतना फर्क सामाजिक मूल्य या नैतिक मूल्य के तौर पर देश को सहन करना चाहिए और खादी को विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रतीक बनाना चाहिए। इस परिस्थिति में यह भी संभव है कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा हाथ करघा मंडल को आज या कल साथ बैठ कर विचार करना पड़े और जितना सूत आज खादी में अम्बर से बनता है उतना ही सूत हाथ करघा वाले भी अम्बर से बना कर अपने-अपने करघों के लिए हाथ कता सूत ही मुहैया करे। वैसी परिस्थिति में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा हाथ करघा मण्डल एक ही बन सकते हैं और दोनों मिल कर मिलो की प्रतिस्पर्धा में किस तरह से खड़ा हुआ जा सकता है, इस पर विचार कर सकते हैं।

खादी के काम को भविष्य में इन दो में से किसी एक पद्धति से चलाना होगा। खादी को ग्रामाभिमुख होना

पड़ेगा तथा जीवन निष्ठा के आधार पर घर-घर में अपने लिए सूत कातना और गाँव में ही उसका कपड़ा बना लेने की दिशा में प्रयास करना होगा। जिसको हम जीवन-पद्धति कहते हैं, उसको अपना कर खादी का कार्यक्रम बनाना चाहिए। दूसरी ओर खादी को विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रतीक मानना चाहिए और उसकी प्रक्रियाओं में विज्ञान और तकनालाजी का जितना उपयोग हो सके उतना करना चाहिए। भविष्य में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा हाथ करघा मंडल को एक करने का भी विचार करना चाहिए। और संभव है कि २० अक तक का सूत हाथ से ही कते और मिलो में उस अक तक का सूत कातना बन्द हो, इस दिशा में सोचना होगा।

समन्वय

दोनों प्रवृत्तियों में सामन्वय लाने का प्रयास आज हो रहा है। शहरो में करोड़ों रुपये की खादी बेचना चालू रहे और गाँव में भी खादी का काम आगे बढ़ाया जाय। खादी धीरे-धीरे ग्रामाभिमुख बने, गाँव की कपड़े की आवश्यकता पूरी होने के बाद ज्यादा कपड़ा शहर में आये। इस तरह का मेल बैठाने का प्रयास बुनाई उपदान के नये तरीके से करने का आज विनोबाजी तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा सोचा जा रहा है। इस तरह से यदि दोनों विचारों का समन्वय किया जा सकता है तो वह अच्छा ही होगा, ऐसा मानना चाहिए। संभव है कि यदि गाँव की सहकारी सेवा समिति की तरफ से खादी कार्यक्रम अपनाया जाय और मुख्यतः गाँव में ही खादी का इस्तेमाल हो, इस तरह से योजना बनायी जाय तो उस परिस्थिति में खादी के प्रमाण-पत्र आदि की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। खादी के औजारो में कितना सुधार हो और उनमें बिजली लगे या नहीं आदि के बारे में गाँववाले अपनी दृष्टि से सोच कर कार्यक्रम बना लेंगे। इस तरह से यदि खादी को प्रमाण-पत्र से मुक्त कर सकते हैं और वह खादी आम जनता का आर्थिक कार्यक्रम बन जाती है तथा गाँव के उद्योगों की नींव इससे पड़ती है तो एक क्रांतिकारी

काम खादी से सिद्ध होगा, ऐसा कहा जायगा। उस परिस्थिति में किसी तरह का आग्रह न खादी और ग्रामोद्योग कमीशन रखेगा और यदि वह रखना चाहेगा तो भी लोग उसका अमल अपने-अपने क्षेत्र में अपने ढंग से ही करेंगे।

नयी दिशा

आज करीबन ७०-८० हजार गाँवों में जो पुराना काम चल रहा है, उसको नयी दिशा में मोड़ने का प्रयास व्यवस्थित ढंग से खादी और ग्रामोद्योग कमीशन कर रहा है। उसके लिए तफसील में योजना बनायी गयी है और आज के काम का परिवर्तन किस तरह से करना है, आदि सोचा जा रहा है। हिसाब आदि के पत्रक भी गहराई में जाकर बनाये गये हैं। जिन्होंने इतना सारा प्रयास किया है उनको जरूर धन्यवाद देना चाहिए, ऐसा सारा देखने के बाद लगेगा। लेकिन सही परिवर्तन इस तरह से नहीं हो सकेगा। मुख्य सवाल है मानस परिवर्तन का तथा लोगों को शिक्षा देने का, कत्तिनो और बुनकरो का सगठन खड़ा करने का, उनके द्वारा पूरे गाँव का सगठन करने का और उसी के माध्यम से गाँव की पूरी आर्थिक योजना बनाने का। इस दिशा में विचार करने पर मुझे लगता है कि पुराने काम को नयी दिशा में मोड़ना बहुत कठिन है। इसके साथ-साथ यदि कुछ शक्तिशाली कार्यकर्ता नया क्षेत्र लेकर शुरू से ही खादी बनाने की दृष्टि से काम का आरम्भ करते हैं तो, उससे सफलता अधिक मिलने की संभावना है। कातने की मजदूरी से कत्तिनो को सगठित करना एक चीज है और अपने-अपने कपड़े के लिए घर-घर में कातो, सिखाने का प्रबन्ध गाँव की तरफ से हो तथा बुनाई भी गाँव की तरफ से हो, इस तरह से काम शुरू करना दूसरी चीज है। यह पुराने ढंग से काम करने की बजाय अधिक आसान रहेगा। इसलिए मैं खादी कार्यकर्ताओं के सामने एक विचार रखना चाहता हूँ कि वे अपने में से कुछ कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नये क्षेत्र में जहाँ आज चरखा नहीं चलता है, ग्रामाभिमुख खादी का प्रयोग करने के लिए मुक्त करे, और उनका यह प्रयोग सफल हो, इसके लिए हर तरह से मदद करे।

एकाध विकास खण्डों में जहाँ पहले से बिल्कुल कताई नहीं होती है, नये ढंग से ही ग्रामाभिमुख खादी का कार्यक्रम हाथ में लेना हो, तो वह किस तरह से हो सकता है, उस पर रायपुर सम्मेलन से ही मैं विचार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत इन सबको इस कार्यक्रम के साथ संबंधित करना चाहिए और उनकी सद्भावना व सहयोग इस काम में प्राप्त करना चाहिए। प्राथमिक शालाओं की मार्फत इस नये कार्यक्रम का श्रीगणेश करना चाहिए। संभव है कि यदि प्राथमिक शाला में अबर चलाना हो तो दो तकुएवाला ही चलाना होगा। नये सिरे से बुनकरो को भी इस कार्यक्रम में शामिल करना होगा। विद्यार्थी अपने खुद के लिए शाला में ही खादी बना ले, ऐसा कार्यक्रम तय करना होगा या टेबल लूम जैसे नये औजारों से २०-२२ इंच अर्ज का कपड़ा शाला के विद्यार्थियों की मार्फत बुनने का कार्यक्रम भी साथ-साथ हाथ में लेना होगा। कताई के साथ बुनाई की भी तालीम बच्चों को मिलेगी। शिक्षकों को भी उस तरह की तालीम देनी होगी और संभव है कि उनको आज के वेतन से इस काम के लिए कुछ अधिक वेतन भी देना होगा। एक-एक शाला यदि वस्त्र स्वावलम्बी हो जाती है तो, उनके द्वारा उनके बालकों तक पहुँचने की तैयारी हो गयी है, ऐसा मान कर एक-एक कदम गाँव को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना होगा।

शुरू से ही खादी अपने लिए ही बनानी है, इस विचार से काम हाथ में लिया जाय और बाल सेना की मार्फत उसका आरम्भ किया जाय। इस तरह का काम यदि किसी क्षेत्र में हाथ में ले सकेंगे तो संभव है कि ग्रामाभिमुख खादी की अच्छी बुनियाद हम डाल सकेंगे और गाँव को ग्राम-स्वराज्य की तरफ ले जाने की प्राथमिक तैयारी कर सकेंगे। ग्रामदान भी उसी में से निकल सकेगा। ग्राम अपने संरक्षण की दृष्टि से शान्ति सेना भी खड़ी कर सकेगा। ऐसा गाँव प्राथमिक आवश्यकताओं की दृष्टि से स्वावलम्बी होगा, शिक्षण भी नये ढंग से चलेगा और रक्षण भी वह अपने आप शान्ति सेना द्वारा कर लेगा।

नयी दिल्ली २८ जनवरी १९६४

मधुमक्खी-पालन उद्योग की समस्याएँ*

राम सुभग सिंह

समय आ गया है कि मधुमक्खी-पालन को कृषि तथा उद्यान-विज्ञान का क्रियाशील सहयोगी माना जाय। परागाधान सेवा के रूप में मधुमक्खियों से काम लेकर फलोद्यानी और बागवान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाकर और राष्ट्र के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की सेवा प्राप्त कर मधुमक्खियों की परिपूर्ण उपयोगिता तथा सभाव्यता प्रकाश में लायी जा सकती है।

कुत्तुट-पालन व सुअर-पालन की भाँति मधुमक्खी-पालन में भी खाद्य के लिए बहुमूल्य पदार्थ तथा पालको व अन्य लोगो के लिए अतिरिक्त आय प्रदान करने आदि की बहु-उपयोगी सभावनाएँ हैं। एक समय था जबकि मधुमक्खी-पालन समय काटने के लिए या शौक के लिए या अन्य मरोरजन का साधन माना जाता था। बाद में इसने गृह-उद्योग का स्तर प्राप्त किया। अब समय आ गया है जबकि मधुमक्खी-पालन को कृषि तथा उद्यान-विज्ञान का क्रियाशील सहयोगी मानना चाहिए। मधुमक्खियों ने न केवल कुछ अच्छी कविताओं को जन्म दिया है वरन् समाजशास्त्रियों को समाज-संगठन के महत्व व रचना के सम्बन्ध में कई अच्छे विचार भी प्रदान किये हैं। इन सब की वजह से तथा प्रेरणा व शक्ति के अन्य बहुतेरे स्रोतों के कारण व विशेष कर आर्थिक दृष्टि से मधुमक्खी-पालन को हमारे देश में बराबर प्रश्रय मिलना चाहिए व उसका पूर्ण विकास किया जाना चाहिए।

देवताओं का आहार

कहा जाता है कि मधु देवताओं का आहार है। विज्ञान के द्वारा भी यह सिद्ध हो चुका है कि मानव से बहुत पहले भी पृथ्वी पर मधुमक्खियाँ रहती थी। इसलिए पहले पहल जब मनुष्य का आविर्भाव हुआ तो उसको मधु ही

मिठास का एकमात्र निश्चित स्रोत और तुरन्त ही काम में लाये जानेवाला आहार उपलब्ध हुआ। मिठास के दूसरे स्रोत जैसे चीनी, शक्कर, गुड आदि को बनाना मनुष्य ने बहुत बाद में जाना। इसका कारण यह है कि ये पदार्थ मधु की तरह सघन, शुद्ध और तुरन्त काम में लाये जानेवाले रूप में नहीं पाये जाते और इन को इस रूप में तैयार करने और भंडारण योग्य बनाने के लिए मनुष्य को रस निकालने, उसको साफ करने और उसको उबाल कर गाढ़ा बनाने आदि के अनेक जटिल तरीके सीखने और विकसित करने पड़े। दूसरी ओर आदि मानव को आदिकालीन मधुमक्खी के छत्ते से उसी प्रकार का शुद्ध शहद प्राप्त होता था जैसा कि आज मनुष्य को आधुनिक मनुष्य कृत पेटी-छत्तो (बी-हाइव) से प्राप्त होता है।

कठिन समस्याएँ

आदिकाल से ही केवल दो प्राणी—गाय और मधुमक्खी—मनुष्य को ऐसे मिले जो क्रमशः अपना दूध और शहद देकर मानवता का स्वागत करने और मनुष्य के साथ सहयोग करने के लिए राजी तथा तैयार थे। सम्भवतः ससार के सबसे प्रथम खाद्य मंत्री अथवा उसी के तुल्य पदाधिकारी ने इन दोनों प्राणियों को ही मनुष्य के सबसे सघन, पोषक, स्वादिष्ट और तैयार भोजन का स्रोत पाया होगा।

बागवानों को यदि मधुमक्खियों की विभिन्न जातियों से मिलनेवाली सहायता रोक दी जाये तो उनको अपने

* त्रिवेन्द्रम में २८ से ३० जनवरी १९६४ तक सम्पन्न पंचम अखिल भारतीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन में दिशा गया उद्घाटन भाषण।

बाग-बगीचों से प्राप्त होनेवाली फलों आदि की फसले मिलनी असम्भव हो जाये। भारत की शहद देनेवाली मधुमक्खी न केवल मधुमक्खी-परिवार की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है, बल्कि वह गाय की ही भाँति सहज में ही पाली जा सकती है। मधुमक्खी बाग-बगीचों और खेतों में खड़े वृक्ष और पौधों को फँसलाने में उनका परागण करने के लिए अनन्त मजदूरो का काम करती है। इसलिए इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि मधुमक्खी की उपयोगिता और सभावनाओं के बारे में अब तक जो कुछ खोजबीन का काम किया गया है उससे कहीं अधिक खोज होनी चाहिए। यह काम तभी संभव हो सकता है, जबकि राष्ट्र के प्रतिभावान वैज्ञानिकों को इसमें लगाया जाये।

हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से मधुमक्खी विकास की समस्याएँ अन्य पालतू प्राणियों के विकास, उदाहरण के लिए पशु-विकास, की समस्याओं से कहीं अधिक कठिन हैं। उदाहरणार्थ गाय को खूटे से बाँध कर पाला जा सकता है किन्तु मधुमक्खी को बाँध कर नहीं पाला जा सकता, क्योंकि पेटी-छत्तों में मधुमक्खी-पालन के लिए मधुमक्खियों को इच्छानुसार आने-जाने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी आवश्यक है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक

मौन-पालक को मधुमक्खी पालने के लिए उनको भोजन, आवास और वातावरण की कहीं अधिक अच्छी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी, जो प्रकृति द्वारा उनको प्राप्त है। इनके अभाव में मधुमक्खियाँ पेटी-छत्तों का त्याग करके अपनी मन-पसन्द का छत्ता कहीं और बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही इस बारे में भी बहुत ही गहन और मौलिक अध्ययन की जरूरत है कि ये मधुमक्खियाँ अपने जीवन से संबंधित इन भिन्न-भिन्न पहलुओं के प्रति विभिन्न स्थितियों में कैसा व्यवहार करती हैं। यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि मधुमक्खियाँ लाठी से हाके जाने वाले पशुओं जैसी नहीं होती। उन्होंने अपना एक अत्यन्त

संगठित सामाजिक ढाँचा विकसित कर लिया है, जिसका कुछ अनुमान हाल में की गयी उन खोजों से लगाया जा सकता है जिनसे पता चला है कि मधुमक्खियों की अपनी एक गव-भाषा होती है, जिसमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय बोलियाँ भी पायी जाती हैं। इसलिए यदि हम मधुमक्खियों के साथ कोई लाभकर साझेदारी करना चाहते हैं तो हमें उनके प्रति अत्यन्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

लाभदायक धंधा

यह सचमुच बड़ी अच्छी बात है कि भारत की अनेक सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं ने, विशेष रूप से स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद, मधुमक्खी-पालन को विकसित करने और उसको ऊँचा उठाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन जैसी संस्थाओं ने अनुसंधान कार्य को गहराई से करने और विस्तार कार्यों को बढ़ाने के लिए नये-नये कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। कमीशन ने देश के विभिन्न भागों में गाव के लोगों को मधुमक्खी-पालन में प्रशिक्षण देकर, आर्थिक सहायता द्वारा उपकरणों को रियाती दरों पर बनाने और मधुमक्खी क्लबों की स्थापना करके इस उद्योग को ग्रामीण भारत में लोकप्रिय बनाने में सहायनीय काम किया है। किसानों और देहात के अन्य लोगों के लिए मधुमक्खी-पालन न केवल मन बहलाने के लिए एक अच्छा शौक ही सिद्ध होगा, वरन् वे शहद और मोम बेच कर अपनी आमदनी में कुछ वृद्धि भी कर सकेंगे। किन्तु भारत में शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अपने देश में ७-८ पौंड प्रति पेटी-छत्ता शहद का उत्पादन होता है। यह बहुत कम है। दक्षिण अफ्रीका के अकेले एक पेटी छत्ते से २,००० पौंड से भी अधिक शहद प्राप्त होने की बात इसका प्रमाण है कि इस धंधे के गर्भ में भारी सम्भावनाएँ मौजूद हैं।

मधुमक्खी का पराग-वाहक के रूप में उपयोग करने से यह धंधा व्यापारिक दृष्टि से और भी अधिक लाभकारी

बन गया है। विदेशो में किसान और बागवान मधुमक्खियों के पेट्टी-छत्तों को किराये पर लेकर उपज बढ़ाने के लिए अपने खेतों और बागों में रखते हैं और ऐसा करने से आम तौर पर उपज २५ प्रति शत तक बढ़ जाती है। इसीलिए मधुमक्खियों के छत्तों का किराया भी (प्रति फसल ५० रुपये तक) अच्छा खासा मिलता है। हमें भारतीय दशाओं में इन सभी सम्भावनाओं का अध्ययन करना है। यदि भारतीय मधुमक्खियों की क्रियाशीलता को बढ़ा दिया जाये, तो मधुमक्खी-पालन के इन विभिन्न पक्षों को मूर्त रूप प्रदान कर इस ध्वेको काफी लाभकर बनाया जा सकता है। यह तभी सम्भव है जबकि हम अब तक के विकसित ज्ञात वैज्ञानिक तरीकों को काम में लाये और भारतीय दशाओं से संबंधित विशेष समस्याओं का हल खोजने के लिए गम्भीर अध्ययन और खोजबीन करें।

मधुमक्खियों का आहार

इन में से कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा जिनका समाधान वैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता से किया जा सकता है। मधुमक्खियों की उन नस्लों से जिनका शहद-उत्पादन कम होता है, चयन और प्रजनन की विभिन्न विधियों को अपना कर उन्नत नस्लें प्राप्त की जा सकती हैं। सभी जानते हैं कि सुनियोजित चयन और प्रजनन द्वारा वैज्ञानिक पशुओं, भेड़ों और मुर्गियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सफल हुए हैं। पशुओं में मूल नस्लों का सुधार करने से आज ऐसी उन्नत नस्लें प्राप्त कर ली गयी हैं जिनका उत्पादन दूध, मांस, ऊन और अंडों के रूप में उन नस्लों से कहीं अधिक है जिनसे इनका विकास हुआ है। मधुमक्खियों के विकास के लिए भी ऐसी ही विधियाँ अपनायी जानी चाहिए और यह संभव भी है। कुछ देशों में मधुमक्खी प्रजनन की तकनीक को सुधारने में भारी सफलता मिली है—यहाँ तक कि मधुमक्खियों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए विशेष उपकरण तैयार किये गये हैं। इस जानकारी का अलग-अलग जलवायुवाले प्रदेशों के लिए मधुमक्खी की

उपयुक्त नस्लें तैयार करने के लिए लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन इस खोजबीन के साथ-साथ भारतीय मधुमक्खियों के वंशीय गुणों से संबंधित पक्षों पर भी गहन अध्ययन करना आवश्यक होगा।

अनेक प्रदेशों में मधुमक्खियों के आहार की समस्या के कारण मौन-पालन का धवा सीमित पैमाने पर ही चलाना पड़ता है। कुछ विशेष मौसमों में तो लगभग संपूर्ण देश में ही आहार की समस्या के कारण मधुमक्खी-पालन का रूप बहुत सीमित हो जाता है। देश में पशुओं के लिए भी तो कभी-कभी चारे की समस्या इतनी ही गम्भीर हो जाती है। किसी पशु या पौधे की बढवार अपने वातावरण से प्राप्त होनेवाले पोषण पर निर्भर करती है। अगर किसी पशु को अच्छी खुराक न मिले या किसी पौधे को अच्छी खाद न मिले तो उसका पूरा विकास नहीं हो पाता। यही बात मधुमक्खियों पर लागू होती है। इसलिए जिन दिनों मधुमक्खियों को प्राकृतिक स्रोतों से उपलब्ध आहार की कमी पड़ जाती है उस समय के लिए उनको पूरक भोजन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी सख्या और मधु-रस-संचय की प्रक्रिया घटती जायेगी और वे अच्छी खुराक की तलाश में अपना छत्ता छोड़ कर चली जायेगी। पिछले कुछ वर्षों में ही पोषण और पोषण-शरीर-रचना से संबंधित विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। उपयोगी पशुओं के लिए सश्लेषित और अर्ध-सश्लेषित खाद्य पदार्थ तैयार किये जा रहे हैं और विदेशों में तो ऐसा खाद्य तैयार करने की खोज काफी आगे बढ़ चुकी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय वैज्ञानिक भी इस दिशा में इतनी ही नहीं, वरन् इससे भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

स्वास्थ्य समस्याएँ

अन्य प्राणियों की तरह मधुमक्खियों के भी प्रकृति में शत्रु होते हैं। यह अच्छी बात है कि भारत में मधुमक्खियों की वे बहुत-सी घातक बीमारियाँ नहीं होती जो यूरोपीय देशों की मक्खियों के लिए बहुत खतरानाक सिद्ध होती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम भारतीय मधुमक्खियों

से शहद उत्पादन के बहुत ऊँचे नतीजे प्राप्त कर सके, हमें उनके स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित समस्याओं पर भली-भाँति विचार करना होगा। भारत में इस समस्या पर काफी ध्यान नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि कुछ मौन-पालकों के लिए पतंगों के सूड़े एक समस्या बन जाते हैं। इस तरह की समस्याएँ दूर-दूर पर स्थित प्राकृतिक छत्तों की तुलना में मनुष्य-कृत पेटी-छत्तों में वहाँ ज्यादा गंभीर रूप धारण कर लेती हैं जहाँ एक ही जगह पर काफी पेटी-छत्तों में मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। यह स्वाभाविक है कि एक ही जगह इतने अधिक छत्तों देख कर पतंगों उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और छत्तों में पतंगों के सूड़े छा जाते हैं। इन हानिकारक सूड़ों के कारण मधुमक्खी की कालोनी में सभी प्रकार की मूसीबतें पैदा हो जाती हैं। क्योंकि केन्द्रीकरण से सदैव ही स्वास्थ्य की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, इसलिए मधुमक्खी उद्योग के बढ़ने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी ये समस्याएँ भी और ज्यादा गंभीर रूप धारण करती जायेगी। इस पृष्ठभूमि में आवश्यक सावधानी और उपयुक्त वैज्ञानिक खोजबीन के महत्व पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए और इसलिए मधुमक्खी रोग-निदान विज्ञान का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

पौध-रक्षण की समस्या

जटिलताओं से व्याप्त इस जगत में मनुष्य का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको अलग रख कर प्रगति की जा सके। हर काम का प्रभाव अनेक दूसरे कामों पर भी पड़ता है। मधुमक्खी-पालन के बारे में भी यह बात लागू होती है। मधुमक्खियाँ सरसों आदि की फसलों और फल-वृक्षों के फूलों पर जाती हैं और उनसे पुष्प-रस या पराग या दोनों लेती हैं। उनकी इस प्रक्रिया से अनजाने में ही फूलों में सकर परागण हो जाता है। यह सभी जानते हैं कि इन सभी फसलों और वृक्षों पर अनेक हानिकार कीट आक्रमण करते हैं और यह पौध-संरक्षण अधिकारी का काम है कि वह इनको हानिकार कीटों से बचाये। मधुमक्खी और उस जैसे अनेक पराग-वाहक कीड़ों को

नुकसान पहुँचाये बिना ही, हानिकार कीटों को नष्ट करने के लिए कीट-नाशकों के उपयोग में बड़ी चतुराई की आवश्यकता है। अच्छा यही है कि हम दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाये और इस प्रकार की आशकाओं के विरुद्ध आवश्यक सावधानी बरते। यदि पौध-संरक्षण अधिकारी और मधुमक्खी-पालन के धंधे को विकसित करनेवाले कार्यकर्त्ता इस दिशा में मिल-जुल कर काम करें तो इस देश में उपर्युक्त आशंकित विनाश से बचा जा सकता है।

शहद को उपचारित करने और संग्रह करने की विधियों का शुद्धता के मापदण्डों से सीधा संबंध है। शहद में मिलावट और उसकी पहचान की समस्या कुछ चिन्ता का विषय बन गयी है। संसार में एक ओर तो रसायन-निर्माता, दिन-प्रति-दिन उपयोग में आनेवाले प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के स्थानापन्न पदार्थों का संश्लेषण कर रहे हैं और दूसरी ओर वे इन संश्लेषित पदार्थों की प्राकृतिक वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम में लगे हुए हैं। संभवतः ये दुतरफे काम साथ-साथ चलते रहेंगे और इन दोनों ही क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना वैज्ञानिकों की जिम्मेवारी है।

शहद की मक्खियों के पेटी-छत्तों का निर्माण, आकार और विस्तार आदि की समस्याएँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। शहद निकालने की पुरानी विधि से मधुमक्खी-पालन के बजाय मधुमक्खी विनाश ही होता था। शहद निकालने की इस विधि में मधुमक्खियों के अड़े-बच्चे इतनी बड़ी संख्या में मर जाते थे कि इससे मनुष्य की आत्मा भी काप उठती थी। संभवतः आरम्भ में मधुमक्खी-पालन का विकास तेजी से न होने का कारण यह भी रहा हो। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में एक अमरीका निवासी ने मधुमक्खियों के लिए लकड़ी-पेटी के रूप में कृत्रिम (पेटी) छत्तों का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने दुनिया भर में मधुमक्खी-पालन के संबंध और तरीकों में एक क्रान्ति मचा दी। तभी से मधुमक्खी-पालन बाकायदा एक विज्ञान बन गया है। अब भी इन छत्तों के निर्माण और उनके वातावरण में सुधार के लिए काफी गुंजाइश है।

पंजाब की अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ

विक्टर सा. डी'सोजा

प्रस्तुत लेख में पंजाब की अर्थ-व्यवस्था के निम्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है आबादी का घनत्व और वृद्धि-दर, कर्मी आबादी में पुरुष और महिला कर्मियों का अनुपात, तथा बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप।

इस लेख का उद्देश्य बहुत सीमित है—पंजाब में रोजगारी और बेरोजगारी के स्तर पर प्रकाश डालना तथा बेकारी के सम्भाव्य कारणों को दर्शाना। तालिका १ से यह देखा जा सकता है कि अखिल भारत की तुलना में पंजाब अधिक घना बसा है, पिछले जनगणना दशक में वहाँ की आबादी में अधिक तीव्रता से वृद्धि हुई है। आबादी में पुरुषों की संख्या ज्यादा है और कुछ शहरी भी अधिक है। यद्यपि पंजाब में १९६१ में साक्षर

चन्द्र गुणों में अन्तर तो बहुत ही स्पष्ट है। जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया है, भारत में आबादी का करीब ४३ प्रति शत कर्मी आबादी है, पंजाब में वह सिर्फ ३५ प्रति शत ही है। भारत और पंजाब की कर्मी आबादी में महिलाओं का प्रातिशत्य क्रमशः ३१.५ और १८.८ है। पुरुष आबादी में पुरुष कर्मियों और महिला आबादी में महिला कर्मियों का प्रातिशत्य भी पंजाब में भारत की तुलना में कम है— महिलाओं के

तालिका १

भारत और पंजाब की चन्द्र जनानिकीय विशेषताओं की तुलना

		भारत	पंजाब
प्रति वर्ग मील घनत्व	१९६१	३७०	४३०
जन संख्या वृद्धि (प्रातिशत्य)	१९५७-१९६१	२१.५०	२५.८६
लिंगानुपात	१९६१	९४६	८६२
प्रति १,००० में साक्षरों का अनुपात	१९५१	१६६	१५२
	१९६१	२४०	२४२
शहरी आबादी (प्रातिशत्य)	१९५१	१७.३५	१९.०१
	१९६१	१७.९७	२०.१३

स्रोत भारत की जनगणना, १९६१ का पेपर संख्या १।

लोगों का प्रातिशत्य करीब-करीब भारत के बराबर ही था, तथापि पिछले दशक में वहाँ साक्षरता की गति अधिक तीव्र रही। इसी अवधि में शहरीकरण में भी पंजाब में भारत की बनिस्बत अधिक तेजी से वृद्धि हुई।

पंजाब और भारत के बीच कार्यकारी शक्तियों के

मामले में ये यह भारत का करीब-करीब आधा है। प्राथमिक कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या पंजाब में करीब ६५ प्रति शत है, जब कि भारत में ७२ प्रति शत। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक श्रेणी के धंधों में भारत और पंजाब के मामलों में पुरुष कर्मियों का वितरण भिन्न है, तथापि दोनों ही मामलों में कर्मी महिलाओं का अनुपात समान है।

तालिका २

भारत और पंजाब की कर्मों शक्ति की विशेषताओं की तुलना (१९६१)

(१)	(२)	प्रत्येक श्रेणी में कर्मों शक्ति में व्यक्तियों का अनुपात			कर्मियों का औद्योगिक वितरण		
		पुरुष	महिलाएँ	योग	प्राथमिक	माध्यमिक	तृतीयक
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
भारत (१९६१)	३१५	५७१२	२७९६	४२९८	६७९८	१२६८	१९३४
पंजाब (१९६१)	१८८	५२९२	१४२०	३४९७	६१२९	१५५२	२३१९
पंजाब (१९५१)	२१३	५५५७	१७५४	३७९९	६५१२	९३२	२५५६

महिलाएँ			योग		
प्राथमिक	माध्यमिक	तृतीयक	प्राथमिक	माध्यमिक	तृतीयक
(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
८१५८	९५९	८८३	७२२८	११७०	१६०२
८०३४	१०५१	९१५	६४८६	१४५८	२०५६
७५१८	८३४	१६५०	६७२७	९१०	२३६३

स्रोत भारत की जनगणना, १९६१ का पेपर संख्या १

आर्थिक प्रगति का प्रभाव

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जैसे-जैसे समाज की सामाजिक अवस्था सुधरती है, माध्यमिक और तृतीयक श्रेणी के धंधों का अनुपात प्राथमिक धंधों की कीमत पर बढ़ता जाता है। तदनुसार यह स्पष्ट है कि पंजाब की अर्थ-व्यवस्था भारत की अपेक्षा अधिक उन्नत है। मैंने अन्यत्र^१ यह दिखाया है कि भारत में जैसे-जैसे सामाजिक अवस्था सुधरती जाती है, आबादी का कर्मों अनुपात घटता जाता है। यह मुख्यतः दो कारणों से होता है प्रथम, नये लोग, अधिक बड़े होने पर धंधों में आते हैं और द्वितीय, बहुत-सी महिलाएँ काम छोड़ देती हैं। भारत से विपरीत पंजाब की अवस्था उपर्युक्त सूत्र की पुष्टि करती है। पंजाब में १९५१ की तुलना में १९६१ में प्राथमिक धंधों में लगे लोगों का

अनुपात कम हुआ है— १९५१ में यह अनुपात ६७.३१ प्रति शत था, जो कि अर्थ-व्यवस्था में प्रगति दर्शाता है। तदनुसार १९६१ में १९५१ की तुलना में (अ) आबादी में कर्मियों, (आ) पुरुष आबादी में पुरुष कर्मियों, और (इ) महिला आबादी में महिला कर्मियों का अनुपात घटा है। शहरी अर्थ-व्यवस्था ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से स्पष्ट बहुत उन्नत है और जैसा कि तालिका ३ से प्रकट है शहरी क्षेत्रों में भी उपर्युक्त श्रेणियों में कर्मियों का अनुपात कम है।

जिले-जिले में भिन्नता

अकेला पंजाब राज्य ही सम्पूर्ण देश से भिन्न हो, ऐसी बात नहीं है, पंजाब के अन्दर भी हर जिला उपर्युक्त गुणों में एक-दूसरे से भिन्न है। सच तो यह है कि कुछ मामलों में तो इन जिलों की भिन्नताएं भारत

१. विक्टर सा० डी'सोजा • पुना की अर्थ विज्ञान नामक पत्रिका के वर्ष १ अंक ३ सितम्बर १९५६, पृष्ठ २३३-२४७

पर प्रकाशित लेख 'इम्प्लीकेशन्स आफ ओक्यूपेशनल प्रेस्टीज फार इम्प्लायमेंट पॉलिसी इन इंडिया।'

तालिका ३

लिंग और औद्योगिक श्रेणियों के अनुसार १९६१ में पंजाब के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्म-शक्ति का प्रतिशत विभाजन

विवरण	ग्रामीण	शहरी
कर्म शक्ति में महिला कामगार (प्रातिशत्य)	२१३	७०
प्रत्येक श्रेणी की कर्म शक्ति में व्यक्ति (प्रातिशत्य)		
पुरुष	५३५	५०९
महिलाएं	१६५	४७
कुल	३६२	३०२
कर्मियों का औद्योगिक वितरण		
पुरुष		
प्राथमिक	७४२	९३
माध्यमिक	१२०	२९९
तृतीयक	१३९	६०९
महिलाएं		
प्राथमिक	८४५	१८३
माध्यमिक	९१	३१२
तृतीयक	६४	५०५
योग		
प्राथमिक	७६४	९९
माध्यमिक	११३	३००
तृतीयक	१२२	६०१

स्रोत भारत की जनगणना, १९६१ का पेपर सख्या १।

के विभिन्न राज्यों के बीच की भिन्नताओं से भी अधिक है। तालिका ४ के प्रसंग में चन्द विशेषताओं में जिलों के बीच वर्तमान भिन्नताओं पर विचार करना उपयोगी होगा। माध्यमिक और तृतीयक धंधों का संयुक्त अनुपात—जो की आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचकांक है—कागडा के १६ प्रति शत से जालंधर के ५७ प्रति शत तक है, शहरी आबादी का अनुपात लाहौल और स्पीति तथा कागडा के क्रमशः शून्य और ४ प्रति शत से लेकर शिमला के ४८ प्रति शत है, साक्षर लोगों का अनुपात सगरूर के १६ प्रति शत से शिमला के ४४ प्रति शत तक है, महिला आबादी में महिला कर्मियों

का अनुपात कपूरथला के ३ प्रति शत से लाहौल-स्पीति के ७० प्रति शत है, और आबादी में कर्मियों की संख्या कपूरथला और लुधियाना के २९ प्रति शत से लाहौल-स्पीति के ७० प्रति शत तक है।

शहरीकरण

तालिका ४ में शहरी आबादी के अनुपात के आधार पर जिलों की सूची अवरोह क्रम से दी गयी है। तालिका पर एक सरसरी नजर डालने से भी इस बात का विश्वास हो जायगा कि अन्य 'चर' (वैरियेबल) शहरी 'चर' से बहुत अधिक सम्बन्धित है। स प्रकार माध्यमिक और तृतीयक श्रेणी का अनुपात उच्च होने, साक्षर व्यक्तियों का अनुपात अधिक होने, महिला आबादी में महिला कर्मियों का अनुपात थोड़ा होने और आबादी में कर्मियों का अनुपात कम होने से शहरीकरण की भी सीमा बढ़ती है। हा, विशेष अवस्थाओं के कारण कुछ खास अपवाद भी हैं, जैसे अधिक शहरीकरण होने के बावजूद शिमला जिले में महिला आबादी में महिला कर्मियों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है तथा कुल आबादी में भी कर्मियों का अनुपात अधिक है। ऐसा इसलिए है कि शिमला जिले के शहरी केन्द्र मुख्यतः 'पर्वतीय स्थान' हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से जिले के बाहर से सैर करने के लिए आनेवालों पर निर्भर हैं और ग्रामीण आबादी आर्थिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा वर्ग है। वस्तुतः शहरी महिला आबादी में महिला कर्मियों का अनुपात सिर्फ ५८ प्रति शत है जब कि ग्रामीण महिला आबादी में उनका प्रातिशत्य ४९ है। इस प्रकार शिमला जिले की शहरी आबादी सम्पूर्ण जिले की सामाजिक अवस्था का परिचायक नहीं है। फिर, भटिण्डा और फिरोजपुर जिलों में उनके शहरीकरण की तुलना में माध्यमिक और तृतीय श्रेणी के धंधों का अनुपात कम है। इन जिलों की शहरी आबादी हाल के वर्षों में व्यावसायिक कृषि में वृद्धि होने से बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है।

तालिका ४ में दिये गये सामाजिक प्रगति के

सभी सूचकांको पर विचार करने पर ऐसा लगेगा कि पंजाब का मध्यम भाग— जिसमें भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और अम्बाला जिले आते हैं— अपेक्षाकृत अधिक उन्नत है। मध्यम भाग में जो जिले जितनी ही दूर हैं, उनका विकास कभीबेश उतना ही कम है। इस प्रकार मध्यवर्ती भाग अपने दोनों ओर के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा है। इसके मुख्य अपवाद दो ही जिले— रोहतक और गुडगाव हैं, जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं तथा अधिकाधिक उसी के प्रभाव

में आ रहे हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण पंजाब और विभिन्न जिलों की कर्मि शक्ति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सामाजार्थिक अवस्था में सुधार होने के साथ आबादी में कर्मि शक्ति का अनुपात घटा है। पहले की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि सामाजार्थिक अवस्थाओं में अधिक सुधार होने पर आबादी में कर्मियों की संख्या और गिरने की सम्भावना है। यह गिरावट मुख्यतः महिला कर्मियों का अनुपात महिला आबादी और कर्मि आबादी, दोनों में ही घटने की वजह से है। तथापि, परिवर्तित सामाजार्थिक

तालिका ४

जिलों में चन्द सामाजार्थिक चरों का प्रातिशत्य वितरण (१९६१)

जिला	शहरी आबादी (प्रातिशत्य)	माध्यमिक व तृतीयक श्रेणी के कामों में कामगार (प्रातिशत्य)	साक्षर आबादी (प्रातिशत्य)	महिला आबादी में महिला कर्मि (प्रातिशत्य)	आबादी में कामगार (प्रातिशत्य)
शिमला	४८१	५२१	४३६	३०६	५०६
अम्बाला	३२०	५२५	३००	६५	३२७
लुधियाना	३०८	५५४	३६३	३६	२८८
अमृतसर	३०२	५२८	२९७	३२	२९९
जालंधर	२८५	५६९	३३७	४०	२९५
पटियाला	२४७	४१४	२४८	३३	३०९
कपूरथला	२३०	४४३	२९४	२९	२८९
भटिण्डा	२१२	३००	१८९	८४	३४२
गुरदासपुर	२०२	५०५	२५३	३७	२९५
फिरोजपुर	२०१	३२७	३२६	९६	३४३
करनाल	१७१	३३२	१८३	१२१	३४२
सगरूर	१६९	२७१	१६५	११७	३५९
गुडगाव	१६६	२९०	२०५	२५५	३९३
हिसार	१५६	२००	१७४	२६७	४२०
रोहतक	१३७	२८२	२१३	२८७	३९०
होशियारपुर	११९	३८७	२८८	११२	३२१
महेन्द्रगढ़	९७	१८४	१८०	२७१	३९०
कागडा	४१	१५७	२३५	४४९	४९८
लाहौल और स्पीती		३१७	१७५	६८९	७०१
पंजाब	२०१	३५१	२४२	१४२	३५०

स्रोत भारत की जनगणना, १९६१ का पेपर संख्या १।

अवस्थाओं का विभिन्न सामाजार्थिक स्तरों पर महिला रोजगारी पर अलग ही प्रभाव पड़ा है। सामाजार्थिक अवस्थाओं में सुधार होने से जहाँ निम्न स्तरों की अधिकाधिक महिलाएँ कर्मी शक्ति से हट सकती हैं वहाँ उच्च स्तरीय महिलाओं में कर्मी शक्ति में शामिल होने की प्रवृत्ति पायी जाती है। अतः जिन चन्द जिलों में आबादी में महिला कर्मियों का अनुपात बहुत ही कम हो गया है, कुछ समय बाद उच्च स्तरीय महिलाओं के लाभदायक रोजगारी के प्रति उन्मुख होने पर आबादी में महिला कर्मियों तथा साथ ही कुल कर्मियों का अनुपात बढ़ने की संभावना है।

रोजगार सर्वेक्षण

पंजाब में रोजगारी और बेरोजगारी की स्थिति की जाच अब ऊपर कर्मी शक्ति के सम्बन्ध में किये गये विश्लेषण के आधार पर की जा सकती है। सम्पूर्ण राज्य के लिए रोजगारी और बेकारी के विश्वस्त सूचकांक उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व 'पेप्सू' सरकार के अर्थ और सांख्यिकी विभाग तथा पंजाब सरकार के अर्थ और सांख्यिकी सगठन द्वारा रोजगारी और बेकारी का पता लगाने के लिए किये गये तीन सर्वेक्षणों के विवरणों में जो विश्लेषण किया गया है, बस वही उपलब्ध है। एक सर्वेक्षण तो १९५५^२ में जालंधर और करनाल जिलों में ग्रामीण बेकारी का तथा बाकी दो सर्वेक्षण पटियाला में १९५३^३ और १९५८^४ में रोजगारी व बेरोजगारी का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं।

इन सर्वेक्षणों में से किसी में भी सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधि नमूना नहीं है। जैसा कि तालिका ४ में देखा जा सकता है, जालंधर और करनाल जिले अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं तथा उनमें आबादी में कर्मियों का

अनुपात अपेक्षाकृत कम है। इसी तरह, पटियाला भी अपेक्षित अधिक विकसित क्षेत्रों में आता है। तथापि, ये अध्ययन पंजाब में रोजगारी और बेकारी की दिशा बताते हैं।

ग्रामीण कार्य

इन तीनों अध्ययनों के आधार पर कर्मी-शक्ति की विशेषताओं का सार तालिका ५ में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में कर्मी शक्ति कुल आबादी की ३४.४ प्रतिशत है। इसमें से ९१ प्रतिशत पुरुष और ९ प्रतिशत महिलाएँ हैं। पुरुष कर्मी पुरुष आबादी का ५६.७ प्रतिशत हैं और महिला कर्मी महिला आबादी का सात प्रतिशत। बेकार लोग कर्मी शक्ति के आठ प्रतिशत हैं और करीब-करीब सभी पुरुष हैं। इनमें से अधिकांश तथ्य तालिका ४ में जालंधर और करनाल जिलों के लिए दिये गये आकड़ों के अनुरूप हैं, लेकिन असाधारण बात तो यह है कि आबादी में कर्मियों का अनुपात ३४ प्रतिशत होने पर भी—जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही कम है—कर्मी शक्ति में आठ प्रतिशत लोग बेकार रहे। दूसरी विचित्र बात यह है कि महिला आबादी में महिला कर्मियों का अपेक्षाकृत कम अनुपात महिलाओं को रोजगारी के अवसर न मिलने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि अधिकांश योग्य महिलाएँ किसी न किसी कारणवश काम करना नहीं चाहती।

महिला कर्मियों का अनुपात

पटियाला के दोनों अध्ययन अधिक जानकारी-प्रधान हैं, क्योंकि वे एक ही स्थान की रोजगारी के विषय में दो अवधियों के तुलनात्मक आकड़े हैं, यद्यपि दोनों अध्ययनों के बीच बहुत कम समय का अन्तर है। पांच वर्ष के अन्तर में ही कर्मी शक्ति में थोड़ा-सा परन्तु

२ रिपोर्ट ऑन दि सर्वे ऑफ रूरल अनइम्प्लायमेंट इन दि पंजाब, आर्थिक और सांख्यिकी सगठन, पंजाब सरकार, आर्थिक जाच मंडल, पंजाब, प्रकाशन संख्या ७९।

३ रिपोर्ट ऑन दि सर्वे ऑफ अन इम्प्लायमेंट इन पटियाला,

१९५४, आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय, 'पेप्सू'।

४ रिपोर्ट ऑन इम्प्लायमेंट एंड अनइम्प्लायमेंट सर्वे ऑफ पटियाला सिटी, आर्थिक और सांख्यिकी सगठन, पंजाब सरकार, प्रकाशन संख्या २६, चण्डीगढ़, १९६०।

तालिका ५

जालंधर और करनाल जिलों के (१९५५ में)
तथा पटियाला जिले के (१९५३ और १९५८ में)
ग्रामीणक्षेत्रों की कर्मी शक्ति की कुछ विशेषताएं

ग्रामीण क्षेत्र पटियाला पटियाला
(१९५५) (१९५३) (१९५८)

आबादी में कर्मी (प्रातिशत्य)	३४४	२५४	२६२
कर्मी शक्ति का लिंग भेद (प्रातिशत्य)			
पुरुष	९१०	९५३	९२७
महिलाएं	९०	४७	७३
पुरुष आबादी में पुरुष कर्मी (प्रातिशत्य)	५५७	४६७	४२७
कर्मी आबादी में महिला कर्मी (प्रातिशत्य)	७१	२६	३८
कर्मी शक्ति में बेरोजगार (प्रातिशत्य)	८०	७४	७४
पुरुष कर्मियों में पुरुष बेरोजगार (प्रातिशत्य)	८७	७०	६७
महिला कर्मियों में महिला बेरोजगार (प्रातिशत्य)	१३	१७३	१५६

स्रोत 'रिपोर्ट ऑन दि सर्वे ऑफ रूरल अनइम्प्लॉयमेंट इन दि पंजाब,' १९५५, 'रिपोर्ट ऑन दि सर्वे ऑफ अनइम्प्लॉयमेंट इन पटियाला,' १९५३, और 'रिपोर्ट ऑन इम्प्लॉयमेंट एण्ड अनइम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ पटियाला सिटी,' १९५८।

सुस्पष्ट परिवर्तन हुआ है। चूँकि विभिन्न पहलुओं में होनेवाले अन्तर स्थायी जैसे हैं, अतएव उन्हें सिर्फ सयोगवश होनेवाले परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। सन् १९५८ में आबादी में कर्मियों का अनुपात थोड़ा सा बढ़ा है। यह मुख्यतः महिला आबादी में महिला कर्मियों का अनुपात बढ़ने के कारण ही हुआ। पुरुष आबादी में पुरुष कर्मियों का अनुपात कम हुआ है, जैसा कि विकासशील समाजों में हो रहा है। फलतः कर्मी शक्ति में महिला कर्मियों का अनुपात इतना बढ़ा है, जो

दिखाई देता है। महिला आबादी में महिला कर्मियों की अनुपात-वृद्धि सामान्य रूप के विपरीत है। यह शिक्षित महिलाओं के उच्च स्तरीय रोजगार में आने के कारण है।

जालंधर और करनाल जिलों के ग्रामीण भाग तथा पटियाला के शहरी भाग की कर्मी शक्ति की अधिकांश विशेषताएं एक-दूसरी से काफी भिन्न हैं एवम् १९५३ व १९५८ में पटियाला की कर्मी शक्ति में भी काफी भिन्नता है, लेकिन जहाँ तक बेकार लोगों के अनुपात का सम्बन्ध है, हर हालत में कर्मी शक्ति का अनुपात बराबर-सा ही है। किन्तु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुसार बेकार लोगों का अनुपात भिन्न है। गावों में जबकि करीब-करीब सभी बेकार लोग—यानी २०३ में से २०० व्यक्ति—पुरुष थे, शहरी क्षेत्र में महिलाओं का अनुपात भी काफी था। सन् १९५३ में १५४ बेकारों में १७ महिलाएँ थी और १९५८ में उनकी संख्या १७८ में ३० थी। कर्मी शक्ति में महिलाओं की कुल संख्या की तुलना में बेकार महिलाओं का प्रातिशत्य १९५३ में १७३ तथा १९५८ में १५६ था। ऐसा लगता है कि पटियाला का व्यावसायिक गठन पहले ऐसा था कि उस में महिला कर्मियों के लिए बहुत कम काम था। चूँकि अधिकाधिक महिलाएँ कर्मी शक्ति में प्रवेश करती जा रही हैं, उन सबको शामिल करने के लिए उपर्युक्त कामों की संख्या पर्याप्त नहीं है और इसी कारण महिला कर्मी शक्ति में बेकारों का अनुपात अपेक्षाकृत ऊँचा है।

बेकारी के आंकड़े

ग्रामीण क्षेत्र में हो अथवा शहरी क्षेत्र में कर्मी शक्ति में बेकार लोगों का अनुपात काफी लगता है। बेकार लोगों की चन्द पिछली प्रासंगिक विशेषताओं का परीक्षण करने से हमें बेकारी के सभाव्य कारणों का सुराग मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार लोगों में करीब २९ प्रति शत तो काम-धंधों में प्रवेश करनेवाले नये लोग थे। करीब ६६ प्रति शत बेकार, युवक वर्ग—

१६ से ३० वर्ष की उम्र के— मे आते हैं, यद्यपि नमूने भिन्न हैं, जैसे कृषि और मजदूरी का काम करनेवाले को सम्पूर्ण रूपेण देखने पर उक्त आयु वर्ग मे खानेवाली लोगो का प्रातिशत्य करीब ६३ तथा ऐसे ही धवो मे आबादी सिर्फ २७ प्रति शत थी। काम चाहनेवाले बेकार लोगो का प्रातिशत्य ४८ था।

तालिका ६

जालंधर और करनाल जिलो में (१९५५ में) सामान्य शिक्षा की दृष्टि से ग्रामीण कर्मी शक्ति का प्रातिशत्य वितरण

सामान्य शिक्षा	अनपढ	प्राथमिक	माध्यमिक	मैट्रिक और	
				ऊपर	योग
रोजी प्राप्त	८०२	८६	५६	५७	१००
नवागतुक बेरोजगार	४३१	१३८	२०७	२२४	१००
अन्य बेरोजगार	७१७	१३१	११०	४१	१००
कुल बेरोजगार	६३६	१३३	१३८	८४	१००
कुल कर्मी शक्ति	७८८	९०	६२	६०	१००

स्रोत पंजाब में ग्रामीण बेरोजगारी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन, १९५५।

तालिका ६ कर्मी शक्ति की शैक्षणिक पृष्ठ भूमि दर्शाती है। यह स्पष्ट है कि रोजगारी मे लगे व्यक्तियो की तुलना मे बेकारो मे अधिक प्रातिशत्य शिक्षितो का है। रोजगारी मे प्रवेश करनेवाले नये लोगो की शैक्षणिक योग्यता और भी अधिक उच्च है। अतः कर्मी शक्ति मे शिक्षितो मे अधिक बेकारी है। नये लोगो मे यह अनुपात सिर्फ ३६ था। इस प्रकार बेकार लोगो के लिए काम की आवश्यकता—खास कर नये लोगो को—भी अभी जो व्यावसायिक स्वरूप है, उससे बिल्कुल अलग है और इससे पूरी नहीं हो सकती। पटियाला मे बेकार लोगो की पिछली विशेषताएँ भी वैसी ही हैं जैसी कि ग्रामीण बेकारो की, लेकिन ये

तालिका ७

पटियाला में १९५३ और १९५८ में लिंग भेद तथा प्रकार के अनुसार बेरोजगारो का प्रातिशत्य वितरण

बेरोजगार व्यक्ति	१९५८ सर्वेक्षण			१९५३ सर्वेक्षण		
	पुरुष	महिलाएँ	योग	पुरुष	महिलाएँ	योग
नवागतुक	५६८	७००	५९०	५८४	६४६	५६५
अन्य	४३२	३००	४१०	४१६	३५३	४३५
योग	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
नमूने मे कुल सख्या	१४८०	३००	१७८०	१३७०	१७०	१५४०

स्रोत पटियाला शहर में रोजगारी और बेरोजगारी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन, १९५८, तालिका ४४।

बेकार लोगो द्वारा वाञ्छित विभिन्न किस्म के व्यवसायो के अनुपात (तालिका मे नहीं दिखाये गये हैं) किये गये दोनो सर्वेक्षणो मे बेकारो का लगानुसार भी वर्तमान व्यावसायिक गठन मे उनके अनुपात से प्रातिशत्य वितरण दिखाया गया है। बेकारो मे नये

लोगों का प्रातिशत्य बहुत अधिक है और पिछले वर्षों में उसमें वृद्धि हुई है। फिर, पुरुष बेकारों की तुलना में महिला बेकारों में नवागन्तुकों का अनुपात दोनों ही सर्वेक्षणों में अधिक था। यह तथ्य उपर्युक्त मत का समर्थन करेगा कि महिलाओं में कुछ बेकारी तो इसलिए है कि वर्तमान व्यावसायिक स्वरूप में महिलाओं के लिए उपलब्ध उपयुक्त कामों की संख्या कहीं शक्ति में नवागन्तुक महिलाओं की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त नहीं है।

बेकारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि

तालिका ८ में दोनों सर्वेक्षणों में बेकारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के सबंध में एकत्रित आकड़ों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। लिगानुसार अथवा नये पुराने के अनुसार १९५३ के सर्वेक्षण में तत्सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है, और इसी तरह दोनों

१९५३ और १९५८ दोनों ही वर्षों में अधिकांश बेकार साक्षर तथा शिक्षित थे। सन् १९५८ में साक्षरों और शिक्षितों का अनुपात बढ़ा है। सन् १९५८ में बेकारों में शामिल होनेवाले नये लोग दूसरों से अधिक शिक्षित थे। अन्य लोगों में जबकि मैट्रिक तथा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त लोगों का अनुपात सिर्फ १६ प्रति शत था, नये लोगों में यह ६१ प्रति शत था। रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों में उनका अनुपात पुराने बेकारों की तुलना में और कम हो सकता है, क्योंकि नमूने में समग्र प्रातिशत्य १२ था। आकड़े यह स्पष्ट बताते हैं कि अशिक्षितों से अधिक बेकार शिक्षित हैं।

तालिका से इस महत्वपूर्ण तथ्य की भी जानकारी मिलती है कि बेकार महिलाओं की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेकार पुरुषों की तुलना में अधिक उन्नत है, दोनों श्रेणियों में मैट्रिक तथा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त

तालिका ८

सामान्य शिक्षा के अनुसार पटियाला शहर में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रातिशत्य वितरण

सामान्य शिक्षा	१९५८ सर्वेक्षण				१९५३ सर्वेक्षण	
	पुरुष	महिलाएं	नवागन्तुक	अन्य	योग	योग
अनपढ़	२२३	२००	६७	४३७	२१९	३३०
प्राथमिक से नीचे	८८		४८	११०	७३	३७१
प्राथमिक	१३५	३३	९५	१५१	११८	
माध्यमिक	१६१	१६७	१८१	१३७	१६३	
मैट्रिक	३११	४००	५०५	६८	३२६	१७५
इण्टर	४१	१३३	३७	८२	५६	१२३
स्नातक व ऊपर	४१	६७	६७	१४	४५	
योग	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
नमूने में संख्या	१४८०	३००	१०५	७३०	१७८०	१४८०

स्रोत पटियाला शहर के रोजगारी और बेरोजगारी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन, १९५८।

सर्वेक्षणों में रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों की शिक्षा के विषय में भी आकड़े प्राप्त नहीं हैं। जो भी हों, उपलब्ध जानकारी अवस्था को बहुत स्पष्ट कर देती है। सन्

व्यक्तियों का अनुपात क्रमशः ७७ और ५६ है। इससे यह पता चलता है कि जहां आम तौर पर समाज की सामाजिक अवस्था सुधरती है, पंजाब के शहरी

क्षेत्रों में महिलाओं में कर्मी शक्ति से हटने का खपाया जाता है, जो कि महिला बेरोजगारी के अविरोधितक पहुँच गया है, वहाँ शिक्षित महिलाओं में कर्मी शक्ति में शामिल होने का झुकाव पाया जाता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि, जब में बेकारी की समस्या में दो मुख्य बातें पायी जाती हैं। एक यह है कि कर्मी शक्ति में शिक्षित व्यक्तियों में अशिक्षितों की अपेक्षा अधिक बेकारी है और दूसरे यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मी शक्ति में बेकारी की समस्या जहाँ मुख्यतः पुरुषों के लिए ही है, वहाँ शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक-शक्ति में बेकार महिलाओं का अनुपात पुरुष कर्मी शक्ति में बेकार पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। इन दोनों बातों से हमें इसका सुराग मिलना चाहिए कि राज्य में बेकारी का मुख्य कारण क्या है। प्रथम प्रक्रिया के लिए मैंने अन्यत्र^५ यह बताया है कि भारत में शिक्षित बेकारों की समस्या मुख्यतः इस कारण है कि शिक्षा और व्यावसायिक गठन के दो परस्पर सम्बन्धित 'चर' असम रूप से परिवर्तित हो रहे हैं, पहले में दूसरे की

अपेक्षा अधिक तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। पंजाब में भी लोगों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि में बहुत अधिक सुधार हुआ है। गत जन-गणना दशक में साक्षरता १५ प्रति शत से बढ़ कर २४ प्रति शत हो गयी है। स्कूलों की संख्या तीन गुनी बढ़ गयी है।^६ व्यावसायिक स्वरूप भी बदल गया है, जैसा कि प्रारम्भ में किये गये विश्लेषण से प्रत्यक्ष है, लेकिन व्यावसायिक स्वरूप में परिवर्तन शिक्षा से अधिक नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में महिला कर्मियों में बेकारी की सीमा शिक्षा और व्यावसायिक स्वरूप के 'चरों' में असम परिवर्तन से भी सम्बन्धित है। महिलाओं की शिक्षा में तीव्र वृद्धि—खास कर शहरी क्षेत्रों में—होने से लाभदायक रोजगारी प्राप्त करने के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। साथ ही शिक्षित महिलाएँ कुछ किस्म के ही काम अपनाने को इच्छुक हैं। फलतः उपलब्ध कार्य, काम चाहनेवाली शिक्षित महिलाओं की बढ़ती संख्या के लिए, पर्याप्त नहीं है।

चण्डीगढ़ : ७ दिसम्बर १९६३

५. विक्टर सा डी सोजा 'सोशल डेवलपमेण्ट, एजुकेशन एण्ड इम्प्लायमेंट इन इंडिया, आगामी डी. पी. मुकर्जी स्मृतिग्रन्थ (मेमोरियल वोल्यूम) में प्रकाशित होनेवाला।

६ स्टेटिस्टिकल एब्सट्रैक्ट ऑफ पंजाब. पंजाब सरकार, आर्थिक और सांख्यिकी सगठन, प्रकाशन संख्या १२, पृष्ठ २४२।

अनुकूल भूमि मनुष्य अनुपात तथा पूर्ण विकसित दुग्ध-उद्योग खेती की कम उत्पादकता के पूरक हैं। राज्य में प्रति एक हजार कृषक पीछे फसली क्षेत्र २,४९० एकड़ है, जबकि सम्पूर्ण देश के लिए यह सिर्फ १,४५० एकड़ ही है। सन् १९५५-५६ में दूध, मक्खन आदि का उत्पादन अन्दाजन ७४ करोड़ ८० लाख रुपये का अर्थात् शुद्ध कृषि उत्पादन का आधा हुआ था। सम्पूर्ण देश में दूध, मक्खन आदि का उत्पादन कुल फसल उत्पादन का मुश्किल से छठा हिस्सा ही हो पाता है। फलस्वरूप कृषि और पशु-पालन में लगे प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादन (४८२ रुपये) राष्ट्रीय औसत (३९८ रुपये) से काफी अधिक है।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात: नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

भारत में मधुमक्खी-पालन

सुभाष चन्द्र सरकार

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के तत्वावधान में हुए प्रयासों के फलस्वरूप मधुमक्खी पालन उद्योग ने काफी रास्ता तय कर लिया है तथा इसके प्रति लोक-अभिरुचि का विकास हुआ है। शहद के मानकीकरण, मूल्य निर्धारण और उसे लम्बे समय तक आरक्षित रखने के लिए तौर-तरीकों सम्बन्धी समस्याओं पर तत्काळ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

पंचम अखिल भारतीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन ने, जिसकी त्रि-दिवसीय कार्यवाही ३० जनवरी १९६४ को त्रिवेन्द्रम में सम्पन्न हुई, मधुमक्खी-पालन के महत्त्व पर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। इसके विकास की भारत में कितनी सम्भाव्यताएँ हैं और अन्यत्र इसका कितना विकास हुआ है, इस दृष्टि से तुलना करने पर भारत में मधुमक्खी-पालन, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष श्री उल्लरगाराय न, डेबर के शब्दों में अभी अपनी 'गर्भावस्था' में ही है। देश में १९६२-६३ के अन्त में १,६३,०१६ मधु-उपनिवेश थे, जिनसे १२,४८,९५९ पौण्ड शहद का उत्पादन हुआ। इस उत्पादन में एक-तिहाई हिस्सा तो अकेले मैसूर राज्य का था। और फिर, मैसूर के ४ लाख ५० हजार पौण्ड मधु-उत्पादन में भी तीन लाख पौण्ड शहद अकेले कुर्ग जिले में तैयार हुआ। व्यावहारिक दृष्टि से मधु-मक्खी-पालन उद्योग मैसूर, मद्रास, केरल तथा किसी हद तक महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर एवम् बिहार राज्य तक ही सीमित है। वैज्ञानिक तौर-तरीकों से मधुमक्खी-पालन का विस्तार करने के लिए १९१८ से प्रयास किये गये, तथापि अभी तक वह गतिशील नहीं हो पाया है। यह सच है कि वस्तुतः मधुमक्खी-पालन की विशाल सम्भाव्यताएँ हैं। भारत के करीब एक-पचमाश हिस्से में जगल है। मधुमक्खी-पालन के लिए वे 'अछूते' क्षेत्र प्रदान करते हैं।

मधुमक्खी-पालन में न तो बहुत अधिक पूँजी की जरूरत पड़ती है और न ही सघन श्रम तथा विशिष्टी-

करण की। साधारण बुद्धि और योग्यता रखनेवाला प्रायः कोई भी व्यक्ति इसे आशिक समय के काम अथवा शौक के रूप में अपना सकता है। सफल मधुमक्खी-पालन प्राविधिक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अर्जित प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर करता है। मधु-पालक को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह है शुरू-शुरू में मधुमक्खी-घर खरीदने के लिए सहायता और प्राविधिक मार्गदर्शन तथा बिक्री के लिए सहायता। शहद प्राप्त करने का परम्परागत तरीका मधु-छत्ता निचोड़ने का है। यह प्रक्रिया ज्यादा खर्चीली है, क्योंकि इसमें बहुत-सी मक्खियाँ मर जाती हैं। वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी-पालन करने पर मक्खियों को बिना कोई नुकसान पहुँचाये मधु-निस्सारण सुनिश्चित होता है।

उपयुक्त नस्लों का विकास

ऐसा पाया गया है कि एपिस इण्डिका नामक भारतीय मधुमक्खी स्थान-विषयक अवस्था के अनुकूल अपने को ढालने में सवेदनशील है। लेकिन फलोद्यान तथा जलवायु जैसे अनेक पहलुओं के कारण उससे शहद की प्राप्ति सीमित मात्रा में ही होती है। अतएव अधिक शहद देनेवाली उपयुक्त नस्लों की मधुमक्खियाँ आयात करने के लिए प्रयास किये गये हैं। तथापि, बाहर से मधुमक्खियाँ मगवाने में एक खतरा यह है कि उनके साथ कुछ सक्रामक बीमारियाँ भी आ सकती हैं, जिनसे देश की मधुमक्खियों का जीवन खतरे में पड़ जायेगा। तथ्य यह है कि भारतीय मधुमक्खियाँ इन रोगों के

प्रति बहुत ही प्रतिरोधी रही है, जोकि अन्य देशों की मधुमक्खियों के लिए एक अन्तर्वर्त भय बना हुआ है। अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरीका यह होगा कि भारतीय मधुमक्खियों में से ही चयन और प्रजनन की विविधा अपना कर उपयुक्त नस्लों का विकास किया जाय। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के तत्वावधान में संचालित मधुमक्खी-पालन अनुसंधानशाला इस कार्य में सलग्न है।

वर्तमान अवस्था

भारत में मधुमक्खी-पालन को यद्यपि राज्य सरकारों से—खास कर मैसूर (भूतपूर्व कुर्ग राज्य के क्षेत्र में), मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में—किसी हद तक प्रोत्साहन मिला, तथापि इसका व्यवस्थित विकास करने के लिए १९५३ में (तत्कालीन अखिल भारत) खादी और ग्रामोद्योग मण्डल ने उसे अपने हाथ में लिया उससे पहले उसके सगठित विकास के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। फिर भी, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उद्योग के विकास में गांधीजी ने भी अपनी दिलचस्पी प्रकट की थी। भारत में वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी-पालन की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देनेवाले हैं फादर न्यूटन, छोटेलालजी (महात्मा-गांधी के निकट सहयोगी), डाक्टर स्पेसर हँच, कुर्ग के स्वामी सम्भवानन्द और श्री सजीव राव कृ कल्लापुर जिन्होंने हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में मधुमक्खी-पालन उद्योग निर्देशक के पद से अवकाश ग्रहण किया है और उक्त कार्य भार उद्योग के प्रवर्तक श्री सीताराम ग शेंडे को सौंपा है।

मधुमक्खी-पालन को प्राविधिक और आर्थिक सहायता देने तथा उन्हें अन्य देशों में वैज्ञानिक तौर-तरीकों से मधुमक्खियों का पालन करने सम्बन्धी प्राप्त ज्ञान की जानकारी करवाने के लिए भी किसी सगठन के अभाव में खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के प्रयास सीमित ही रहे। यह सच है कि अखिल भारतीय मधु-पालक संघ क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन भारत में मधु-पालकों

की सीमित संख्या के फलस्वरूप उसकी सदस्यता व विस्तार की क्षमता बहुत ही सीमित थी। और फिर, इस प्रकार के स्वेच्छित सगठन से वैसे क्षेत्रों में उद्योग का विकास करने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, जोकि उसकी ओर से अछूते रहे हैं। अतएव, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने सहायता देने की एक प्रणाली तैयार की जिसके अन्तर्गत मधु-पालकों द्वारा मधुमक्खी-घरों की खरीद पर उपदान (सब्सिडी) देने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी-पालन हाथ में लेने की जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारी प्रदान करने की कल्पना की गयी। अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की पहल तथा बाद में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन (जिसने अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल से १९५७ में कार्यभार सम्हाला) के प्रयासों के जरिये देश में अनेक मधुमक्खी-पालन उप-केन्द्र, आदर्श मधु-वाटिकाएँ, पौध-शालाएँ, स्कूली मधु-वाटिकाएँ तथा व्यावसायिक रोपण मधु-उद्यान सामने आये हैं। आज सारे भारत में वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी-पालन होता है—यहाँ तक कि उपुसी और नागा प्रदेश जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी। फिलहाल ७९० उप-केन्द्र और ९० सम्भाग हैं, जिनके अन्तर्गत ११,०६७ गाव तथा ५३,८८४ मधु-पालक आते हैं।

उत्पादन और लक्ष्यांक

सन् १९५३-६३ के बीच के दशक में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के मधुमक्खी-पालन कार्यक्रम पर कुल ९० लाख रुपये खर्च हुए। इन में २० लाख पये साधन-सरजाम पर दिया गया उपदान था, जोकि मधु-पालकों द्वारा निर्मित पूँजी परिसम्पत्ति का ५० प्रतिशत हिस्सा है। इसी दशक में मधु-उत्पादन ४८ लाख पौण्ड हुआ, जिसकी कीमत ९६ लाख रुपये होती है। इसमें ५० हजार पौण्ड मोम का अनुमानित उत्पादन भी जोड़ा जा सकता है, जिसका मूल्य एक लाख रुपये होता है। इसके अलावा १ लाख ५० हजार मधु-उपनिवेश स्थापित किये गये हैं। प्रति उपनिवेश १० रुपये का

सामान्य मूल्य मानने पर भी इनकी कीमत १५ लाख रुपये होती है।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना अर्थात् १९७० के अन्त तक भारत में कम से कम कुल १० लाख मधु-उपनिवेश बनाने की योजना है। इनसे प्रति वर्ष एक करोड़ पौण्ड से भी अधिक शहद का उत्पादन हो सकेगा।

परागाधान के लाभ

शहद का पोषण और औषधियों की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। शहद उत्पादन वृद्धि से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ सकता है। मधुमक्खी-पालन तो अकेले इसी आधार पर वाछनीय है। लेकिन मधुमक्खियाँ वनस्पति के क्षेत्र में एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका और अदा करती हैं। वे फूलों के परागाधान के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मधुमक्खी-पालन विकास कृषि और उद्यान विज्ञान के विकास के लिए वरदान सिद्ध होगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री डाक्टर राम सुभग सिंह ने २८ जनवरी १९६४ को पंचम अखिल भारतीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि कुक्कुट-पालन व सुअर-पालन की भांति मधुमक्खी-पालन में भी खाद्य के लिए बहुमूल्य पदार्थ तथा पालको एवम् अन्य लोगों के लिए अतिरिक्त आय प्रदान करने आदि की बहु-उपयोगी सम्भावनाएँ हैं। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियों का पराग-वाहक के रूप में उपयोग करने से यह धंधा व्यावसायिक दृष्टि से और भी अधिक लाभकारी बन गया है।

देश के विभिन्न भागों में गावों के लोगों को मधुमक्खी-पालन में प्रशिक्षण देकर, आर्थिक सहायता द्वारा उपकरणों को रियायती दरो पर बनाने तथा मधुमक्खी-क्लबों की स्थापना करके खादी और ग्रामोद्योग कमिशन ने इस उद्योग को ग्रामीण भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किए हैं। प्रयासों की डाक्टर राम सुभग सिंह ने भी सराहना की थी। उन्होंने कहा, “किसानों और देहात के अन्य लोगों के लिए मधुमक्खी-पालन न केवल मन

बहलाने के लिए एक अच्छा शौक ही सिद्ध होगा, वरन् वे शहद और मोम बेच कर अपनी आमदनी में कुछ वृद्धि भी कर सकेंगे।”

उत्पादकता, मानकीकरण व बिक्री

भारत में प्रति पेटी-छत्ता औसतन सात-आठ पौण्ड शहद उत्पादन अनेक अन्य देशों के लगभग ७० पौण्ड औसत उत्पादन की तुलना में बहुत ही कम है। डाक्टर राम सुभग सिंह ने अपने भाषण में एक सन्दर्भ दिया था कि दक्षिण अफ्रीका में एक पेटी छत्ते से दो हजार पौण्ड वार्षिक तक शहद तैयार होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस उद्योग में भारी सम्भाव्यताएँ निहित हैं।

यद्यपि उद्योग में निहित विकास की सम्भाव्यताओं और देश की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की तुलना में शहद का उत्पादन बहुत कम है, तथापि उद्योग का एकांगी विकास इस बात में प्रतिबिम्बित होता है कि बिक्री की समस्या खड़ी हो गयी है। माल इकट्ठा हो जाने के कारणों का पता लगाना और यह जानना एक तत्काल किया जानेवाला काम हो गया है कि ऐसा शहद की ऊँची कीमतों के कारण हुआ है अथवा उसके गुण-स्तर में कमी होने के कारण या दोनों की वजह से। शहद के मानकीकरण, उसकी कीमत और उसे लम्बे समय तक टिकनेवाला बनाने के लिए तौर-तरीके ढूँढ निकालने पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। शहद की बिक्री को इस कारण भी धक्का लगा है कि अभी तक कोई ऐसा सूत्र नहीं निकाला जा सका है, जिससे उसकी शुद्धता आँकी जा सके। अलग-अलग फूलों से तैयार किये गये शहद की विशेषताएँ भी अलग-अलग होती हैं। मधु-विश्लेषण के विश्वस्त तरीके खोज निकालने के लिए अन्वेषण तथा प्रयोग किये जा रहे हैं।

उद्योग विकास के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन-से क्षेत्र उसके लिए अनुकूल हैं। पंचम अखिल भारतीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन में उड़ीसा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के अध्यक्ष श्री राज कृष्ण बोस ने इस सबंध में एक सुझाव दिया कि देश के विभिन्न

भागों में मधुमक्खी-पालन के विकास की सम्भाव्यताओं का पता लगाने की दृष्टि से समूचे भारत में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सर्वेक्षण में कुछ वर्ष लग सकते हैं, फिर भी वैसा करना मूल्यवान साबित होगा, क्योंकि उसके पूरा होने पर राष्ट्र के पास ऐसे क्षेत्रों की एक सूची होगी, जहाँ उद्योग का विकास किया जा सकेगा।

छत्ते से शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को अब भी देश के अनेक भागों में मार दिया जाता है। अनेक प्रतिनिधियों ने इस बुरी पद्धति का जिक् किया और कहा कि इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। श्री बोस ने एक सुझाव दिया था कि राज्य सरकारें कानून बना कर ऐसी पद्धतियों पर रोक लगावे। सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया। भारत में मधुमक्खी-पालन के विकास के लिए मधुमक्खियों को जीवित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य कोई काम।

संगठन और वित्त

उद्योग की समस्याएँ तीन श्रेणियों में विभक्त की जा सकती हैं (अ) संगठनात्मक, (आ) वित्तीय, और (इ) शैक्षणिक। संगठन की दृष्टि से चार अभिकरण—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल, १९६० के समिति पजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत समितियाँ जिन्हें सामान्यतः 'संस्थाएँ' कहा जाता है, तथा सहकारी समितियाँ—क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देश में पचायत राज की स्थापना के साथ क्षेत्र में पचायत राज संस्थाओं के एक पाचवें संगठन का प्रादुर्भाव और हुआ है। सम्मेलन में इस बात की आवश्यकता पर विस्तार में चर्चा हुई कि किसी स्तर पर इन संस्थाओं की अन्य कार्यशीलताओं में समन्वय हो तथा उनमें संयोजन स्थापित किया जाय। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन उद्योग के विकास हेतु पहले से ही लगभग एक करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। कमीशन देश के मधुमक्खी-पालन उप-केन्द्रों में क्षेत्रीय कर्मचारी नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। प्रथम तीन वर्ष के लिए वह इस प्रकार के

कर्मचारियों का पूरा खर्च बर्दाश्त करता है और उसके बाद के दो वर्ष के लिए वह आंशिक रूप से उक्त व्यय वहन करता है। तत्पश्चात् अर्थात् पांच वर्ष की अवधि के बाद उप-केन्द्रों से अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय कर्मचारियों का खर्च वे बर्दाश्त करें। पांच वर्ष के अन्त में क्षेत्रीय कर्मचारियों का व्यय देना बन्द कर देने के निर्णय के सम्भाव्य प्रभान के सम्बन्ध में सम्मेलन में उपस्थित अधिकांश प्रतिनिधियों ने चिन्ता व्यक्त की।

उपसंहार

कमीशन के अध्यक्ष श्री उछरगराय न डेबर ने यह स्पष्ट किया कि कमीशन का इरादा मधुमक्खी-पालन उद्योग के लिए वित्तीय वितरण रोकना नहीं है। क्षेत्रीय कर्मचारियों का व्यय एक निश्चित अवधि के लिए सीमित रखने के पीछे इरादा यह है कि एक ओर जनता में 'अपनी सहायता खुद करने' की भावना जागृत हो और दूसरी तरफ उद्योग को विस्तृत क्षेत्र में फैलाना सम्भव बने। उन्होंने आगाह करते हुए कहा था कि मधुमक्खी-पालन कार्यक्रम अकेले खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा ही सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के कृषि विभागों के सहयोग का होना अनिवार्य है। यह अपेक्षा करना भी गलत होगा कि उद्योग के विकास के लिए समूचा व्यय कमीशन ही वहन करे। अतएव उन्होंने स्वेच्छित अभिकरणों से उपयुक्त योगदान देने का आवाहन किया। कमीशन अनिश्चित काल तक सहायता देते नहीं रह सकता, और मधुमक्खी-पालन उद्योग को भी अपने पैरों पर खड़ा हो कर प्रारम्भिक अवस्था में जानेवाली सहायता का औचित्य सिद्ध करना चाहिए।

उद्योग के विकास के लिए संगठनात्मक, वित्तीय और शैक्षणिक आधार को शक्तिशाली बनाने हेतु सम्मेलन ने कई प्रस्ताव पारित किये। निस्सन्देह पंचम अखिल भारतीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन भारत में मधुमक्खी-पालन के विकास में एक उल्लेखनीय घटना है। [संक्षेप का संक्षिप्त रूप ९ फरवरी १९६४ के 'दि इकनॉमिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था।]

त्रिवेन्द्रम १० जनवरी १९६४

मधुमक्खी-पालन उद्योग : समीक्षा*

सीताराम गं. शेण्डे

मधुमक्खी-पालन उद्योग ने खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रदत्त सहायता के परिणाम-स्वरूप उल्लेखनीय प्रगति की है। सन् १९७० के अन्त तक भारत में कम से कम दस लाख मधु-उपनिवेश तो हो ही जाने चाहिए, जिनसे प्रति वर्ष एक करोड़ पौण्ड से ज्यादा मधु तैयार हो। कृषिक और वानस्पतिक फसलों में इन मधु-उपनिवेशों से फसल-परागाधान के लिए परिपूर्ण काम लेने से राष्ट्र को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

पिछले वर्षों की प्रगति को देखते हुए मधुमक्खी-पालन उद्योग का विकास काफी उत्साहवर्द्धक है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे खादी और ग्रामोद्योग मण्डलो, सस्थाओ तथा सहकारी समितियों ने उद्योग की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम सहयोग का परिचय दिया है।

मधुमक्खी-पालन उप-केन्द्रों, आदर्श मधु-वाटिकाओं, पौध-घरों, स्कूली मधुवाटिकाओं, व्यावसायिक रोपण मधु-वाटिकाओं आदि की स्थापना जैसी विभिन्न योजनाएँ १९५३ से हाथ में ली गयी हैं तथा कार्यक्रम का विस्तार अब देश के सभी भागों में हो गया है—उपूसी एवम् नागा प्रदेश जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी। आज कार्य का विस्तार ७४ क्षेत्रीय कार्यालयों तक हो गया है, जिनमें ७९० उप-केन्द्र हैं तथा ९० सभाग, जिनके अन्तर्गत ११,०६७ गाव आते हैं। इन गावों में ५३,८८४ मधुमक्खी-पालक हैं, जिनके पास १,६३,०१६ मधु-उपनिवेश हैं। सन् १९६२-६३ में १२,४८,९५९ पौण्ड शहद का उत्पादन हुआ।

सघन तरीकों की आवश्यकता

अगर उद्योग को अधिक लाभदायक एवं मितव्ययी आधार प्रदान करना है, तो महज कार्यक्रम का विस्तार ही पर्याप्त नहीं है। अतः क्रमबद्ध अनुसंधान एवम्

प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये विकसित तकनीकों को प्रयुक्त कर सघन तरीके अपनाने की दिशा में प्रयास करना होगा। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने भी मौन-अनुसंधान क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा पूरे देश के लिए एक विस्तृत योजना अभी-अभी हाथ में ली गयी है। एक केन्द्रीय मौन-अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हो चुकी है तथा अगले दो वर्षों में पांच या छ क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा है। आम जनता को वैज्ञानिक मधुमक्खी-पालन की जानकारी देने तथा यह किस प्रकार अपने सीमित साधनों से राष्ट्र की सामान्य अर्थ-व्यवस्था एवम् कल्याण में योगदान दे सकता है उसके हेतु साहित्य, प्रेस, प्रदर्शनियों, फिल्मों गोष्ठियों आदि के जरिये प्रभावशाली प्रचार करने के लिए जोरदार प्रयास करना होगा।

मुझे अगस्त १९६३ में जेकोस्लोवाकिया के प्राग नामक स्थान पर आयोजित १५वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की ओर से भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस सम्मेलन में ४० देशों के १००० से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, व्यावसायिक मधुमक्खी-पालक तथा मधुमक्खी-पालन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। बहुत-से लोग इस अल्पावधि में ही कमीशन के अन्तर्गत इस क्षेत्र में अब तक प्राप्त सफलता से बहुत प्रभावित

* त्रिवेन्द्रम में सम्पन्न पंचम अखिल भारतीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन में २८ जनवरी १९६४ को दिया गया स्वागत भाषण।

हुए तथा भारतीय मधुमक्खी-पालन के प्रति उन्होंने काफी दिलचस्पी दिखायी। शीघ्र विकास के लिए उन्नत तकनालाजी का फायदा उठाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र में प्रवेश करने का हमारे लिए यह एक अवसर है।

सफलताएँ

गत दशक में इस क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं में ८० प्रति शत से अधिक हिस्सा दक्षिणी राज्यों का रहा, जिनमें प्रथम मैसूर और द्वितीय तथा तृतीय स्थान क्रमशः मद्रास एवं केरल ने प्राप्त किया। अब उत्तरी राज्यों—खास तौर से हिमालयी क्षेत्रों—में मधुमक्खी-पालन उद्योग को विकसित करने का समय आ गया है। अतः हिमालयी क्षेत्रों में अधिक विस्तार केन्द्र खोलने पर जोर दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि थोड़े ही दिनों में उत्तर और दक्षिण की प्रगति में समतुल्य स्थापित हो जायेगा।

आम तौर से यह विश्वास किया जाता है कि मधुमक्खी-पालन से केवल शहद एवम् मोम ही प्राप्त किया जा सकता है। आंशिक रूप में यह सही भी है, परन्तु आज सभी विकसित देशों ने मधुमक्खियों की परागाधान सम्बन्धी सेवा को स्वीकार कर लिया है। आज बहुत-से देशों में कृषि के वैज्ञानिक व क्रमबद्ध विकास की किसी भी योजना में मधुमक्खियों का अभिन्न स्थान है। मौन परागण विश्व-सनीय है तथा उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए भारत जैसा खेतिहर देश मधुमक्खियों की सेवाओं को नजरंदाज नहीं कर सकता।

पिछले दस वर्षों यानी १९५३-६३ में कमीशन के जरिये इस उद्योग पर कुल ९० लाख रुपये खर्च किये गये। इन में से २० लाख रुपये सरजाम उपदान (सब्सिडी) के रूप में वितरित किये गये, जोकि इस प्रकार से निर्मित पूँजी-परिसम्पत्ति का ५० प्रति शत है। इस खर्च पर उक्त दशक (१९५३-६३) में ९६ लाख पये मूल्य के ४८ लाख पौण्ड शहद का उत्पादन हुआ। मोम का अनुमानित उत्पादन ५० हजार पौण्ड था, जिसका मूल्य लगभग १ लाख रुपये होता है।

अतः ९० लाख रुपये के कुल खर्च से ९७ लाख पये की प्राप्ति हुई। इस समय कुल १,५०,००० मधु-उपनिवेश हैं, और १० रुपये प्रति उपनिवेश की दर से

भी उनका मूल्य १५ लाख रुपये होता है। अगर परगाधान के जरिये जगली अथवा कृष्ट आर्थिक वनस्पति क्षेत्रों में हुए अप्रत्यक्ष लाभों को भी हम गिने तो यह शहद और मोम से हुए लाभ से अधिक हो जायेगा।

अतः यह स्पष्ट है कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न उद्योगों में मधुमक्खी-पालन बेहतर स्थिति में है। गत दस वर्षों में इस पर खर्च हुई निधि तथा इससे हुई आमदनी से यह बात सिद्ध हो जाती है कि मधुमक्खी-पालन उद्योग से काफी फायदा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस उद्योग में जितनी पूँजी लगती है अनुपाततः उससे कहीं अधिक लाभ होता है। इस उद्योग पर खर्च हुई रकम से केवल मधुमक्खी-पालकों को ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि बढइयो, टीनकारों तथा अन्य कारीगरों को भी लाभ पहुँचा है। ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मधुमक्खी-पालन उद्योग के न होने से प्रकृति का यह शहद-धन बेकार चला जाता।

भविष्य के लक्ष्यांक

यद्यपि उद्योग की ऊपर वर्णित दस वर्षों की प्रगति काफी प्रशंसनीय रही है, तथापि वह विकास के लिए हमारी प्राकृतिक शक्त का एक अंश भी नहीं है। अतः तीसरी योजना के अवशेष भाग और चौथी योजना की समस्त अवधि में पूरे किये जाने लायक उचित लक्ष्यांक निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। सन् १९७० के अन्त तक, हमें भारत में कम से कम कुल १० लाख मधु-उपनिवेश तो बना ही लेने चाहिए, जिनसे प्रति वर्ष मधु-वाटिकाओं में एक करोड़ पौण्ड से अधिक मधु प्राप्त हो सके। यदि हम इन मधु-उपनिवेशों का कृषि और फलों की फसलों के परागाधान के लिए इस्तेमाल करें तो देश को करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि यह लक्ष्यांक फ्रांस और जर्मनी जैसे चन्द देशों में पाले जानेवाले मधु-उपनिवेशों की सख्या से कम ही हैं, जबकि उनका क्षेत्रफल हमारे चन्द राज्यों के ही बराबर है। अतः १९७० के अन्त तक १० लाख मधु-उपनिवेश बनाने का उपर्युक्त लक्ष्यांक सामान्य और उचित ही है।

मौन-पालन में अनुसंधान *

गोविन्द बालकृष्ण देवडीकर

प्राचीन ढग से मौन-शिकार करने के तरीके को छोड़ मौन-पालन का आधुनिक तरीका हमने इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अपनाया, जबकि हस्तातरित होनेवाली मौन-पेटी बनी। भारतीय मधुमक्खियों के विषय में विस्तृत अनुसंधान कार्यक्रम करीब दस वर्ष पूर्व मद्राबलेश्वर और पूना स्थित मौन-पालन प्रयोगशालाओं द्वारा आरम्भ किया गया, जिन्होंने उन्नत नस्ल, उन्नत चारा और उन्नत मौन प्रबन्ध से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रणी कार्य किया है।

मधुमक्खियों से हमारा सम्बन्ध उतना ही प्राचीन है, जितना कि मानव सम्यता से। इसका आरम्भ तब हुआ जबकि हमारे पूर्वजों ने मधु-छत्ते से प्राप्त शहद का सर्व प्रथम रसास्वादन किया। तब से ही हम मधु-मक्खियों को जला उनके छत्तों को निचोड़ कर शहद निकालते आ रहे हैं। हजारों वर्षों तक हम नम्र मौन-पालक होने के बदले कठोर और क्रुतधन मौन-शिकारी रहे हैं। प्राचीन ढग से मौन-शिकार करने के तरीके को छोड़ मौन-पालन का आधुनिक तरीका हमने इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अपनाया, जबकि हस्तातरित होनेवाली मौन-पेटी बनी। इस खोज के कारण मधुमक्खियों के साथ हमारा सम्बन्ध सुधरा है। आधुनिक मौन-पालन 'जीओ और जीने दो' वाली प्रक्रिया है जिसमें परस्परलाभ और कर्तव्य का ध्यान रखा जाता है।

प्रशंसनीय प्रगति

भारत में मौन-पालन का आरम्भ अपेक्षाकृत कुछ देरी से, इस शताब्दी के प्रथम दशको में हुआ। यह चन्द अग्रणियों के प्रयासों का फल था, किन्तु सगठित प्रयास न होने के कारण तब तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई जब तक कि इस उद्योग के विकास का भार चन्द राज्यों में नवगठित ग्रामोद्योग मण्डलों को न सौंप दिया गया। सन् १९५३ में अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना के बाद मौन-पालन ने बड़ी तीव्र

प्रगति की। अब हमारे देश में ५ लाख से भी अधिक आधुनिक मधु-छत्ते हैं, जिनसे वार्षिक १५ लाख पौड से भी अधिक शहद प्राप्त होता है।

यद्यपि यह प्रगति प्रशंसनीय है, तथापि चन्द देशों के उत्पादन और हमारे ही देश में इस उद्योग के विकास की जो प्राकृतिक क्षमता है उसकी तुलना में नगण्य है। इस प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करने हेतु हमें मौन-पालकों तथा मौन-पेटियों की संख्या तो बढ़ानी ही है, प्रति पेटी शहद का उत्पादन बढ़ा कर उद्योग की योग्यता भी बढ़ानी है। पहले का सम्बन्ध है हमारे मौन-पालन सगठन के विस्तार विभाग से और दूसरे का अनुसंधान विभाग से। अतः मैं यहाँ भारत में मौन-पालन, अनुसंधान की वर्तमान अवस्था का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूँगा।

विस्तृत अनुसंधान

भारत में मौन और मोन-पालन पर वैज्ञानिक खोजें हाल के दशकों में की गयी हैं। अधिकांश प्रारम्भिक कार्य विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थाओं के कीट विज्ञान विभागों द्वारा—विशेष कर पूसा, दिल्ली, कोयम्बतूर, लायलपुर, लुधियाना, कतरन, जेबलीकोट और अन्य केन्द्रों द्वारा—किया गया। प्राणि-विज्ञान विभागों ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी प्रारम्भिक खोजों ने भारतीय मधुमक्खियों के तुलनात्मक आकृति, शरीर, पारिस्थिकी और कुछ हद तक वर्गीकरण विज्ञान पर अधिक जोर दिया। इससे इस विषय में बड़ी मूल्यवान् मूल जानकारी मिली।

* प्रस्तुत लेख पचम अखिल भारतीय मधुमखड़ी-पालन सम्मेलन में पढ़ा गया था।

तथापि, मौन-पालन अनुसन्धान में व्यापक दूरदर्शिता और अभिस्थापना की आवश्यकता है। यह विषय ही ऐसा है कि नेमी कीट-विज्ञानीय पहलुओं के अतिरिक्त विभिन्न जीव-विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में होनेवाली बड़ी ही महत्वपूर्ण खोजों पर भी साथ ही ध्यान देना अनिवार्य है। इसमें ये चीजें शामिल हैं मौन-पौध विज्ञान, मौन रसायन शास्त्र, कोशिकानुवर्तिका, नस्ल सुधारने के लिए प्रजनन, मौन-व्यवहार अध्ययन, कृषि फसल परागण, स्थानीय पारिस्थिकी से सम्बन्धित सही प्रबन्धीक व्यवस्था करना, शहद, मोम तथा अन्य मधु-उत्पादनों का मानकीकरण, आदि।

मौन-पालन प्रयोगशालाओं का योगदान

भारतीय मधुमक्खियों पर इस तरह का विस्तृत अनुसन्धान कार्य सर्व प्रथम दस वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में महाबलेश्वर और पूना की मौन-पालन प्रयोगशालाओं द्वारा आरम्भ किया गया। तब से छोटे और बड़े १,००० मधु-पौधों का, सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया और वार्षिक चक्र में उनके पुष्पीय अनुक्रम निर्धारित किये गये। वार्षिक चक्रों की कमीवाली अवधियों में मधु-रस और पराग उपलब्ध करने के लिए उन अवधियों में फूलनेवाले मधु-पौधों को परीक्षण के लिए लगाया गया।

प्रयोगशाला ने भारत में मेलिटोपैलिवोलाजी अर्थात् मौन-समस्याओं पर पराग प्रयुक्त करने के अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। हजारों से भी अधिक पौध-जातियों के पराग माइक्रोस्लाइड स्थायी तौर पर तैयार किये गये हैं और इनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। इससे एक पुष्पीय और बहु-पुष्पीय शहद के वनस्पति स्रोतों का उनके भौगोलिक मूल के साथ परिचय प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। यदि शहद में किसी विषैले पौधे का पराग हुआ, तो उसका भी इससे पता लग जाता है। इस तरह का पराग विश्लेषण अब नेमी कार्य हो गया है, विशेष कर एक-पुष्पीय शहद को बेचते वक्त। प्रगतिशील मौन-पालन सहकारी समितियाँ वनस्पति स्रोतों की सही जानकारी के लिए कई नमूने प्रयोगशाला

को भेजती हैं।

प्रयोगशाला ने मधुमक्खियों के जरिये चन्द फसलों में सकर-परागण के फलस्वरूप हुई उत्पादन वृद्धि का अन्दाज लगाने के लिए कई प्रयोग किये। मौन-परागण से नीबू, अगूर, रसभरी और चन्द अन्य उद्यानी फसलों में ३० से ९० प्रति शत तक वृद्धि हुई है और फल के आकार, वजन, रंग और सुगंध में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। बैंगन, मिर्च और चन्द किस्म के कुम्हड़ों में भी इसी तरह के परिणाम निकले हैं। प्याज की फसल तिगुनी और नाइजर की पाँच गुनी बढ़ गयी। तरबूज या बादाम जैसे पौधों के फलों में, जोकि बहुत अधिक स्वयम्-वन्ध्य हैं, आप कितनी ही मात्रा में खाद क्यों न डालें, कितनी ही सिचाई या अन्य सिचन व्यवस्था क्यों न करें, बिना मौन या अन्य कीट परागण किये वृद्धि नहीं हो सकती। यदि हम परागण के लिए मधुमक्खियों की व्यवस्था करें तो हमारे अविकाश तिलहनो, दालों, तरकारियों, फलों, कपास और अन्य फसलों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।

बहु-विध जानकारी

प्रयोगशाला ने भारतीय शहद और मौन-मोम के भौतिक और रासायनिक तत्वों के विषय में विस्तृत आकड़े संग्रहीत किये। इन आकड़ों का उपयोग कृषिक हाट-व्यवस्था सग न और भारतीय मानक संस्था ने भारतीय शहद और मौन-मोम की शुद्धता के विशिष्टीकरण हेतु किया। प्रयोगशाला ने योग्य मौन-प्रबन्ध के लिए कई नेमी-क्रियाएँ बनायीं। इनमें खेतों और जंगली क्षेत्रों के बीच स्थानान्तरण पद्धति, कहीं झुड़ बनाने और कहीं छत्ता छोड़ देने को रोकने, मधुमक्खियों को भोजन कराने और उनके छत्ते बदलने की मिश्रित प्रक्रिया, बरसात, जाड़ा, कमी और आधिक्य की अवधियों में सामान्य कार्य पद्धति शामिल हैं।

अण्डशावक और ऊपरी कोठों के अनुकूलतम विस्तार तथा मधुमक्खियों के लिए अनुकूलतम स्थान सम्बन्धी आकड़ों का भारतीय मानक संस्था के सहयोग से मधु-पेटियों और अन्य उपकरणों का मानकीकरण करने में

उपयोग किया गया। एक उन्नत शहद चरागाह इकाई की इजाद की गयी है, जोकि देश के विभिन्न भागों में अपनायी जा रही है।

उन्नत नस्लों का प्रजनन

भारतीय मधुमक्खियों के तुलनात्मक कोशिकानु-वशिकी अध्ययन के आधार पर उन्नत नस्लों के प्रजनन हेतु एक अभिनव पद्धति बनायी गयी। सुबरी नस्लों से सामान्य अवस्थाओं में आम मधुमक्खियों से ३० से ९० प्रति शत अधिक शहद प्राप्त हुआ है। भारत में ऐसा पहली बार किया गया है।

अनुसंधान के अलावा प्रयोगशाला ने प्रगामी मौन पालन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाया है। अब तक भारत, नेपाल और सिक्किम के ७६ प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सदस्य पुस्तकालय में ५,००० से अधिक अनुसंधान निबन्ध हैं, जोकि विभिन्न देशों से हमारे प्रकाशनों के बदलौन से प्राप्त हुए हैं। साव-धानीपूर्वक इनकी सूची तैयार की गयी है, उन्हें वर्गी-कृत किया गया है और उनका सूचकांक बनाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान सत्र ने इसे एशिया की अपनी चन्द शाखाओं में से एक मान लिया है।

प्रयोगशाला के कार्यों को उचित मान्यता देते हुए खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने हाल ही में इस प्रयोग-शाला को केन्द्रीय मौन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था के रूप में पुनर्गठित किया है, जिसका प्रधान कार्यालय पूना में है। यह देश के विभिन्न भागों में स्थापित की जानेवाली करीब सात क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य को समन्वित करेगी। दो की स्थापना तो मरकारा और कोडाईकनाल में हो भी चुकी है।

मौन-पालन उद्योग की उत्पादन-योग्यता अन्ततः उन्नत प्रजनन, उन्नत चारा और उन्नत प्रबन्ध पर निर्भर करती है। हमें मधुमक्खी-उत्पादनों के स्तर नियंत्रण की भी व्यवस्था करनी है, ताकि उपभोक्ताओं के हित की रक्षा हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय संस्था

और क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ जोरदार प्रयास करेगी।

अनुसंधान विभाग को मजबूत बनाने के साथ ही विस्तार विभाग को भी पुनर्गठित करना आवश्यक है ताकि हर मौन-पालक तक तकनीकल सुधार पहुँच जाय। यदि इस कार्य को पूरा करने के लिए विस्तार विभाग को पर्याप्त रूप में सुसज्जित नहीं किया गया तो किसी भी हद तक किया गया प्रयुक्त अनुसंधान महज शैक्षणिक महत्व का ही रह जायगा। अब तक हमारा मौन-पालन कार्य मुख्यतः जंगली क्षेत्रों में, अधिकतर स्थिर अथवा अप्रगामी आधार पर ही सगठित किया गया है। हम स्थानांतरित मौन-पालन—जंगल से खेत और खेत से जंगल में स्थाना-तरण—अपना कर ही महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। अतः विस्तार विभाग में काम करनेवालों को न सिर्फ जंगली क्षेत्रों में मौन-पालकों का संगठन करना है, बल्कि कृषि क्षेत्रों में भी। यदि हम कृषि फसलों के लिए विस्तृत मौन-परागण सेवा का संगठन कर सकें तो अति-रिक्त राष्ट्रीय धन पैदा कर भौतिक योगदान दे सकते हैं।

उपसंहार

यदि हम मौन-परागण सेवा का विस्तृत रूप में संगठन करें तो अतिरिक्त फसल से होनेवाली अन्य रेलवे से होनेवाली वार्षिक राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में मुख्य बाधा है कीटनाशकों का अविवेकपूर्ण उपयोग। अतः किसानों को कीटनाशकों तथा पेस्टीसाइड का विवेकपूर्ण उपयोग—खास कर अलग-अलग फसलों की फूँकोवाली अवधि में—सिखाना होगा। इसके लिए कृषि विस्तार सेवा के साथ निकट सहयोग आवश्यक है। मौन-परागण सेवा में सड़क और रेल के जरिये दूर-दूर तक मधुमक्खियों का स्थानान्तरण भी शामिल है। ये परिवहन सुविधाएँ बहुत ही कम हैं तथा काफी महंगी हैं। यह आवश्यक है कि सरकार इसके लिए रियायती प्रबन्ध करे तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से तुरन्त परिवहन की व्यवस्था करे। हवाई मार्ग से भी रियायती दर पर परिवहन व्यवस्था करना वाछनीय है।

मधुमक्खियां और परागाधान*

हरिहरन विद्वनाथन

परागाधान कार्य में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा महत्व है; क्योंकि मानवीय नियंत्रण में वे ही एकमात्र पराग-वाहक हैं। वस्तुतः मधुमक्खी का मूल्य मधु-उत्पादक की अपेक्षा पराग-वाहक के रूप में कितना ही अधिक है।

खेती के अन्तर्गत ज्यों-ज्यों अधिक जमीन आती जाती है और जैसे-जैसे कृषि का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे पराग-वाहक जंगली जीवों के आश्रय नष्ट होते जाते हैं। पशुओं को चराने के लिए जमीन का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से उक्त हानि और भी अधिक होती है। दावानल, सड़के, रेल की लाइने आदि का भी इस सम्बन्ध में हाथ रहता है। काफी क्षेत्र में एक फसल पैदा होने के कारण उनका विकास तथा अभिवृद्धि डाबाडोल हो जाते हैं। और अन्त में, कीटनाशक तथा तृणनाशक औषधियों के विस्तृत प्रयोग से लाभदायक व हानिप्रद दोनों ही प्रकार के जीवों अर्थात् कीटों का नाश हो जाता है और साथ ही साथ उनके खाद्य का स्रोत भी समाप्त हो जाता है। व्यवहारतः प्रत्येक कृषि विषयक गतिविधि से पराग-वाहक जंगली जीवों का किसी न किसी अंश में ह्रास होता है। इनके अलावा देश में जंगली शहद इकट्ठा करनेवाले व्यक्ति जो विनाशकारी तरीके अख्तियार करते हैं उनसे भी हमारे पहाड़ों व जंगलों में जो प्राकृतिक छत्ते हैं वे धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं। अतएव कृषि को लाभदायक धरा बनाने में सहायक सबसे अधिक लाभदायक जीव मधुमक्खी की रक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए।

अनुमान है कि फलों और बीजों के लिए आवश्यक परागाधान-कार्य का ८० प्रति शत से भी अधिक हिस्सा मधुमक्खियाँ पूरा करती हैं। इस प्रकार कृषि

* पंचम अखिल भारतीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन में प्रस्तुत निबन्ध।

विकास के लिए जोकि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार स्तम्भ है, परागाधान उसकी कुजी बन जाती है। हमारे भावी कृषि कार्यक्रम में आयोजित परागाधान एक सर्वाधिक लाभदायक तथा लोकप्रिय कृषि कार्य बन सकता है।

सर्वोत्तम पराग-वाहक

आयोजित परागाधान किसे कहते हैं ? इसका तात्पर्य है कि जब फसल प्रस्फुटित अवस्था में हो तब अधिकतम बीज कण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सख्या में मधुमक्खिया रखने की व्यवस्था करना। कहा जाता है कि मधुमक्खियाँ पेड़-पौधों की शाखाओं को फलों से लाद देती हैं। विभिन्न फसलों के लिए परागाधान सेवा प्राप्त करने के लिए प्रस्फुटित फसलवाली प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए हो सकता है कि एक से तीन मधु-उपनिवेश रखना आवश्यक हो। मधुमक्खियाँ जितनी अधिक होगी उतनी ही अच्छा है और उन्हें रखना फायदेमन्द भी है। कभी-कभी उपज दुगुनी, तिगुनी और यहाँ तक कि पाँच गुनी तक हो जाती है। परागाधान के लिए मधुमक्खियों के स्थान पर कोई अन्य यांत्रिक तरीका अभी तक खोजा और उपयोग में नहीं लाया जा सका है। यह आगे-पीछे, ऊपर अथवा नीचे की तरफ उड़ सकती है, अपनी इच्छा के मुताबिक किसी भी फूल पर बैठ सकती है, पराग या मधु-रस अथवा दोनों इकट्ठा कर उन्हें भावी उपयोग के लिए अपने छत्ते में ले जाकर जमा कर सकती है। वर्ष भर जीवन और गतिशीलता के साथ भिनभिनाती हुई स्वर-मग्न मधुमक्खियों के बड़े-बड़े उपनिवेश बड़ी-बड़ी नदियों के स्रोतों के पास मिलते हैं।

तथा बारह मास बहनेवाली इस प्रकार की नदियों के किनारों के साथ-साथ उनकी सभ्यता का अवलोकन किया जा सकता है। मधुमक्खी-पालन के आधुनिक तौर-तरीके अपना कर उनकी अवस्था में सुधार किया जा सकता है और मधु के रूप में खाद्य उत्पादन तथा अच्छे फल, बीज आदि के उत्पादन के लिए भी उनका उपयोग किया जा सकता है। इन सभी का बहुत बड़ा मूल्य है और उनका दीर्घ स्तर पर उत्पादन करने का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था व समृद्धि के लिए व्यापक महत्व है।

मधु-उद्यान का स्थान

देश के खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी तरह संचालित मधु-उद्यान को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। सावधानीपूर्वक परिरक्षित मधु-उद्यान मधु-पालकों को खेतों की फसल, फलों के बगीचों और जंगलों तथा खेतों में पैदा होनेवाले फूलों से—जोकि अन्यथा बेकार जाते—अधिक शहद प्राप्त करने में मदद दे सकते हैं। मधु उत्पादन में मददगार होने के अलावा मधुमक्खियाँ परागाधान के काम में भी काफी हिस्सा बटाती हैं। यह निश्चित लगता है कि भविष्य में उन्हें और भी अधिक विस्तृत भूमिका अदा करनी पड़ेगी, मानवीय नियंत्रण में रहने-वाले ये ही एक मात्र पराग-वाहक हैं। अन्य कीट बचाये नहीं जा सकते, लेकिन उपयुक्त सावधानी बरत कर मधुमक्खियाँ नष्ट होने से बचायी जा सकती हैं और उन्हें परागाधानी कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चन्द फूलों का परागण करने के सम्बन्ध में उनकी योग्यता पर शक किया जाता है, किन्तु समग्र रूप से यह माना जाता है कि वे अधिकांश फसलों को उपजाऊ बना सकती हैं, यह कि पराग-वाहक के रूप में उन पर सभी प्रमुख फसलों के लिए विश्वास किया जा सकता है और वे उत्कृष्ट फल प्राप्त कर सकती हैं।

प्रस्फुटन-काल में अन्य सभी प्रकार के जीवों से पहले मधुमक्खियाँ परागण कार्य में व्यस्त हो जाती हैं। यही नहीं, इस अवधि के अन्त में वनस्पति परित्याग भी वे सब

जीवों के बाद करती हैं। एक प्रकार के फूल से दूसरे प्रकार के फूल तक बार-बार मण्डरानेवाली अन्य मक्खियों व जीवों के विपरीत मधुमक्खियों में प्रत्येक प्रकार के फूल पर कम से कम कुछ समय तक बैठने की आदत होती है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि फलों, सर्वाधिक प्रमुख खाद्यान्न फसलों और बीजों—खास कर द्विदलीय किस्मों—तथा अन्य नकद फसलों के लिए सफल पराग-वाहक के रूप में मधुमक्खियों के बराबर अन्य वाहक नहीं हैं। इस सम्बन्ध में उनका मूल्य बहुत ऊँचा है—मधु-उत्पादन के रूप में उनका जो मूल्य है, उससे भी कितना ही अधिक। कहा जाता है कि यदि वे शहद एक रुपये का पैदा करती हैं तो वैसा करने में वे फल पैदा करनेवाले को १०-१५ रुपये अधिक के फल पैदा करने में सहायक होती हैं।

सफल परागाधान

बेहतरीन फसल-प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए परागाधान सेवा का सफल संगठन अवश्य ही किया जाना चाहिए। इसके लिए मधुमक्खी-पालन की दृष्टि से उन्नत विदेशों में मधुमक्खियों के आवास की अच्छी व्यवस्था होती है और साथ ही उनकी अच्छी निगरानी रखी जाती है। वहाँ से जहाजों के जरिये उनका आयात किया जाता है। उन्नत कृषि और फल पैदा करने के लिए मवेशियों, भेड़ों तथा अन्य इसी प्रकार के पशुओं के समान मधुमक्खियाँ भी आवश्यक हैं। उन्नत खेती बेहतर जमीन की व्यवस्था और कुशल साधन-संरजाम के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती। जब तक खेतों में प्रस्फुटित फूलों पर मधुमक्खियों का आवागमन नहीं होता और वे परागाधान नहीं करती, तब तक इन्हीं से अधिकतम उपज नहीं मिल सकती। इसके लिए उन्नत खेतों के सन्दर्भ में मधु-उद्यान का होना एक आवश्यक कारक बन जाता है।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र सघ की सरकार ने पुनर्स्थापन की जो योजनाएँ हाथ में लीं उनमें एक थी कृषि विस्तार के लिए सस्ते बीजों का दीर्घ स्तर पर उत्पादन करना। इसके लिए उन्होंने मधुमक्खियों

की सहायता ली। जिन क्षेत्रों में बीज उत्पादन मुख्य उद्देश्य था वहाँ काफी तादाद में मधुमक्खियों के छत्ते वितरित किये गये। प्राप्त परिणामों से उन्नत बीज उत्पादन की दृष्टि से मधुमक्खियों का महत्व प्रतिष्ठापित हुआ।

बहु-विध लाभ

भारत जैसे विशाल और खेती प्रधान देश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी-पालन का विस्तार करने से होनेवाले लाभों को रुपये-पैसे की शब्दावली में आकना मुश्किल है। मधुमक्खी-पालन से न केवल अनेक लोगों को रोजगारी मिल सकती है तथा करोड़ों रुपये मूल्य के पौष्टिक खाद्य पदार्थ मधु का, और मोम का उत्पादन हो सकता है—जिसकी भी काठ और चमड़े के लिए अच्छी

पालिस तैयार करने, मोम बत्तियों, साबुन, जलावरोधी सामग्री आदि बनाने में उपयोग होने के कारण व्यावसायिक दृष्टि से बहुत मँग है—बल्कि यदि देश में उसका विस्तृत पैमाने पर विस्तार किया जाय तो ऐसा लगता है कि देश की कृषि तथा बागवानी पर भी उसका बहुत अच्छा एवम् गहरा प्रभाव पड़ेगा। अधिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी-पालन का कितना बड़ा महत्व है, सामान्य किसान को उसकी जानकारी करवानी पड़ेगी। मधु-उद्यान खड़े करने के लिए—फिर चाहे उनका स्तर छोटा हो अथवा बड़ा—किसान को प्रोत्साहन देना चाहिए। मधुमक्खियों के जीवित रखने और अधिक उत्पादन का परस्पर चोली-दामन का सम्बन्ध है। ●

INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS

(Organ of the Indian Society of Agricultural Economics)

Vol XVIII

OCTOBER-DECEMBER 1963

No 4

ARTICLES

A Review of Measures of Farm Income for International Use

Robert D Stevens

Problems of Mechanization in Indian Agriculture

Theodor Bergmann

Land Reform and Land Prices

G Wunderlich

NOTES

Economics of Drill Sowing over Broadcasting in Ragi

N P Patil

An Aspect of Development Impact of a Simple Pattern of Trade between Two Countries

(Smt) V Mukerji

Note on Research in Agricultural Economics in India 1957-62

BOOK REVIEWS

Per copy Rs 4 00 for regular issues and
Rs 6 50 for the Conference
Number — postage extra

REVIEWS IN BRIEF

Annual Subscription
Rs 15 00 — post free

Hon Secretary

THE INDIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ECONOMICS,

46-48, Esplanade Mansions,
Mahatma Gandhi Road, Fort,
BOMBAY-1

आधुनिक मधुमक्खी-पालन*

जे. राजय्या

मद्रास राज्य में मार्तण्डम का मधुमक्खी-पालन केन्द्र एक ऐसा केन्द्र है, जो विद्यालयों और गांवों में मधुमक्खी-पालन को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक उत्साहवर्द्धक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

अनादि काल से मनुष्य एक श्रेष्ठ भोज्य वस्तु तथा औषधि के रूप में मधु के मूल्य से परिचित रहा है। भारतवर्ष में तो यहाँ तक रिवाज है कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले उसे शहद ही चटाया जाता है। औषधि के रूप में उसका उपयोग क्षेत्र इतना विस्तृत है कि प्रायः सभी प्रमुख देशी औषधियों के साथ शहद का प्रयोग होता है। पुराने रोगों में प्रयुक्त होनेवाली समस्त औषधियाँ मधु-मिश्रित होती हैं, जिससे शारीरिक प्रक्रिया में शीघ्र मिल कर काम करने में मदद मिलती है।

इस आश्चर्यजनक खाद्य पदार्थ को तैयार करनेवाले छोटे-छोटे जीवों को मधुमक्खी कहा जाता है, जो अपने लोकतांत्रिक समाज में वास करती हैं। ये इतनी समझदार होती हैं कि एक उपनिवेश की रहनेवाली मक्खियाँ, अपने कार्यों में, मधुरस-संग्रह में या खाने-पीने में कभी एक-दूसरी से नहीं लड़ती। उनके काम बटे होते हैं और सब अपनी-अपनी भूमिका अदा करने में जुटी रहती हैं। लेकिन दूसरे किसी उपनिवेश की मधुमक्खी अगर उनके बीच आ गयी तो वे कभी उसकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे मार निकालने की कला भी वे अच्छी तरह जानती हैं।

मधु, फूलों के मधुरस का एक गाढ़ा तरल स्वरूप है, जो मधुमक्खियों द्वारा मधुरस-संचय करने के बाद उनके छाव से मिल कर ओर परिष्कृत हो कर तैयार होता है। गीष्म काल में मधुमक्खियाँ विभिन्न फूलों का मधुरस लेकर अपनी मधु-शैलियों में संग्रह करती जाती हैं और

फिर अपने छत्तों में ले जा कर उस छत्ते के खानों में जमा करती हैं, उन दिनों के लिए जब सारे फूल झड़ जाते हैं और जब उन्हें भूखो रहना पड़ता है या ठंड के दिनों के लिए। मधुमक्खियों की मधु-शैलियों में छाव से मिल कर उस मधुरस में रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है और काफी हद तक उसका जल-तत्व सूख जाता है। और, इस प्रकार मधु-तैयार हो कर एक ऐसा खाद्य पदार्थ बन जाता है, जिसकी बराबरी करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है।

जल का प्रातिशत्य

यो तो मधुमक्खियाँ प्रायः समस्त भोज्य फूलों के मधुरस का पान करती हैं, पर वे सब फूलों का मधुरस जमा नहीं करती। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार मधुमक्खियों द्वारा 'सिलो' में जमा किये गये मधु में लगभग १८ प्रति शत जलाश रहता है। छब्बीस प्रति शत से अधिक जलाश-वाला मधुरस आसानी से संग्रहीत नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, ताड़ का रस, जिसमें ८६ प्रति शत से अधिक जलाश होता है, मधुमक्खियाँ संग्रह नहीं कर सकती। किन्तु ताड़ की जटा (फूलों) से वे मधुरस ग्रहण कर लेती हैं। इसी कारण इस प्रकार संग्रहीत मधु में ताड़ रस की खुशबू आती है। खाद्य पदार्थ के रूप में इस मधु का मूल्य अधिक होता है। आम के बोर से प्राप्त मधुरस काफी गाढ़ा होता है। विभिन्न प्रकार के मधुरस में कितना जलाश होता है, इसका पता मधुमक्खियों को रहता है, और इस मामले में वे बड़ी चालाक होती हैं कि किस प्रकार का मधुरस जमा करना है। जो भी मधुरस उनकी मधु-शैली में जायेगा, मधु बन जायेगा।

* पंचम अखिल भारतीय मधुमक्खी-पालन सम्मेलन में प्रस्तुत निबन्ध।

मधु का रग और स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मधुरस किस फल से सग्रहीत है।

अनादि काल से ही मधु का मूल्य जान लेने के बाद मनुष्य उसे सग्रह करने की कोशिश करता रहा। किन्तु उसने जो तरीके अपनाये, वे अपरिपक्व और अवज्ञानिक रहे। प्रायः मधु-छत्तो को आग दिया कर मधुमक्खियों को जला दिया जाता या उन्हें उड़ा दिया जाता और छत्तो को अड़ो सहित निचोड़ कर मधु निकाला जाता। मधु रखने का तरीका भी बहुत अस्वास्थ्यकर था। यह अवस्था १७ वीं शताब्दी तक जारी रही, जब डच वैज्ञानिक स्वामेरेडैम (Swamerdam) ने मधु-उपनिवेश में रानी मक्खी के महत्व का पता लगाया। तब तक लोगो का ऐसा खयाल था कि मधुमक्खी परिवार का प्रबान कोई नर मक्खी होता है। उसके बाद रोमर (Reammer) नामक वैज्ञानिक ने अनेक अनुसंधान और प्रयोगों के जरिये एक झुण्ड बना कर उड़ जाने की मधुमक्खियों की मनो-वृत्ति तथा अपनी सख्या बढ़ने पर नयी रानी मक्खियों की स्थापना करने आदि का पता लगाया। उन्होंने सर्व प्रथम मधुमक्खियों के कृत्रिम छत्ते बनाये और मधु तथा अड़ो के लिए अलग-अलग खाने बना कर प्रयोग किये। इस सम्बन्ध में और भी खोजे होती रही और झिरझो (Dzierzon) नामक व्यक्ति ने पहले पहल कृत्रिम छत्ते में चल फ्रेम का प्रयोग किया। उसके बाद लैंगस्ट्राथ (Langstrath) ने उपनिवेश में मधुमक्खियों के बैठने की दूरी (बी स्पेस) का पता लगाया। ह्रुस्का (Hruschka) ने मधु-निस्सारक का पता लगाया, जिससे छत्ते को बिना कोई नुकसान पहुँचाये शुद्ध-मधु निकाल लिया जाता है।

मधुमक्खियों का ज्ञान

इस विषय पर बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन अपने ४० साल के अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर ए. आय. रूट ने जो पुस्तक लिखी है, वह पश्चिम में वैज्ञानिक मधु-पालन पर पूरी जानकारी देती है। भारतीय मधुमक्खियों (एपिस इंडिका) के सम्बन्ध में के. चन्द्र दासगुप्त की पुस्तक 'रोमास ऑफ साइंटिफिक

बी-कीपिंग' अच्छी जानकारी उपस्थित करती है। मद्रास में मार्तण्डम स्थित वाय. एम. सी. ए. के मधुमक्खी-पालन के तत्कालीन कार्यभारी मंत्री जे. दासप्पा की पुस्तक 'ए. हैड बुक ऑफ माडर्न बी-कीपिंग' भी इस विषय पर काफ़ी व्यावहारिक जानकारी प्रदान करती है।

स्तरीय मधु-छत्ते

भारत में वैज्ञानिक मधुमक्खी-पालन का प्रारम्भ १९०३ में इटलीवासी फादर न्यूटन ने किया था, जो एक रोमन कैथोलिक के रूप में त्रिची आये थे। वे अपने देश में मधुमक्खियों पालते थे और यह उनके जीवन का एक ऐसा धवा बन गया था, जिसे भारत आने पर भी वे छोड़ नहीं सके। किन्तु भारतीय मधुमक्खियों के लिए एक स्तरीय पेटी छत्ता बनाने में उन्हें मेहनत करनी पड़ी। कहा जाता है कि फादर न्यूटन की प्रेरणा में पूसा कृषि कालेज के आचार्य सी. सी. घोष ने १९०७ में लकड़ी के बने पेटी छत्तो की ईजाद की, जिसमें उन्होंने भारतीय मधुमक्खियों रखी तथा उन्हें बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाये मधु निकालने की प्रथा शुरू की। इन पेटी छत्तो को अपनी प्रथम पुस्तक 'पूसा बुलेटिन ऑन बी-कीपिंग' में घोष ने 'न्यूटन किस्म के छत्ते' कहा है।

मार्तण्डम में मधुमक्खी-पालन के विकास कार्यों का श्रेय डा. हैच को है, क्योंकि वे स्वयम् अमेरिका में यह कार्य करते थे और यहाँ आने पर बड़े पैमाने पर इस कार्य को शुरू किया। मार्तण्डम के चारों तरफ १५ मील के दायरे में समस्त गाँवों में उन्होंने इसका प्रचार शुरू किया और प्रायः प्रत्येक बाजार, स्कूल तथा कालेज में वाय. एम. सी. ए. के प्रशिक्षित कर्मचारी आधुनिक पेटी छत्तो में मधुमक्खियों को पकड़ कर रखने तथा वैज्ञानिक तरीकों से मधु-निस्सारण के तरीकों का प्रदर्शन करते थे। इसकी देखा-देखी स्कूल जानेवाले बच्चे, शिक्षक तथा होशियार ग्रामीणों ने भी मधुमक्खी-पालन शुरू किया। सार्वजनिक चन्दे से सागौन की लकड़ी के पेटी छत्ते बनाये गये और रियायती दर पर गरीबों में वितरित किये गये। फिर धीरे-धीरे लोग स्थानीय लकड़ियों से छत्ते बनाने लगे

और क्रमशः इस उद्योग का विस्तार दक्षिण भारत के गाँवों में होने लगा। समीप के इलाकों से और दूर-दूर से भी बहुत-से छात्र प्रशिक्षण के लिए आने लगे।

प्रारम्भ में प्रत्येक मधुमक्खी पालक सिर्फ दो या तीन छत्ते रखा करता था और जो कुछ मधु वह प्राप्त कर पाता था सिर्फ उसके अपने उपयोग में ही आता था। पर जैसे-जैसे उनके अनुभव बढ़ते गये, उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती गयी और उन्होंने अधिकाधिक छत्ते रखना शुरू किया। इसके परिणाम-स्वरूप अधिक मधु का उत्पादन होने लगा और उसकी बिक्री की कोशिश की जाने लगी। यही से मार्तण्डम मधुमक्खी-पालक सहकारी समिति के सगठन को प्रश्रय मिला। उन दिनों की प्रगति बड़ी तेज थी, किन्तु पर्याप्त निधि की कमी के कारण समिति इस अवस्था में नहीं थी कि उत्पादकों का सारा मधु खरीद सके और इस वजह से मधु-पालक भी अपने धबके के भविष्य के बारे में बड़े चिंतित थे। किन्तु अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल तथा उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की स्थापना से इस उद्योग में नयी जान आ गयी है।

फिलहाल मार्तण्डम क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत ३२ मधुमक्खी उप-केन्द्र, ३ मधुपौध-शालाएँ तथा एक आदर्श मधु-उद्यान है। इलाके के ४२८ गाँवों के ३,५२८ बाशिन्दों के बीच रियायती दरों पर सागवान की लकड़ी

के बने १४,००० पेटी छत्ते वितरित किये गये। एक छत्ते से औसतन लगभग ११ पौंड मधु पैदा होता है और उत्पादक को प्रति पौण्ड डेढ़ रुपया मिलता है।

इसके अतिरिक्त १६ विद्यालयों में मधुमक्खी-पालन शुरू किया गया है, जिनमें से प्रत्येक स्कूल में १२ वर्ष से अधिक उम्र के लगभग ३० बालकों को प्रति वर्ष मधुमक्खी-पालन का सघन प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत-से प्रशिक्षित बालकों ने अपने घरों में मधुमक्खी-पालन शुरू कर दिया है और वे मधु का उत्पादन कर रहे हैं। इस मधु को वे खाते भी हैं और उससे कुछ कमाई भी कर लेते हैं। जिन विद्यालयों में मधुमक्खी-पालन शुरू किया गया है, उनमें से प्रत्येक में औसतन ७३० छात्र पढ़ते हैं। इस प्रकार $७३० \times १६ = ११,६८०$ छात्र मधुमक्खी-पालन की शिक्षा ले रहे हैं। पिछले ग्रीष्म काल में १,५०० मधु-उपनिवेशों को पड़ोस के रबड़ के बगीचों में स्थानांतरित किया गया, जहाँ दो महीने के अन्दर प्रत्येक पेटी छत्ते से १३ पौंड मधु प्राप्त हुआ।

उक्त केन्द्र में कुछ ग्रामीण मधुमक्खी-पालक भी हैं, जिनमें प्रत्येक १०० से अधिक पेटी छत्ते रखता है। इस प्रकार वे पेशेवर मधुमक्खी-पालक बन गये हैं और पर्याप्त आय कर रहे हैं। अन्दाज है कि मार्तण्डम केन्द्र में कोई १३,७०० मधु-उपनिवेश हैं, जिनमें रबड़ के बागीचेवालों के मधु-उपनिवेश भी शामिल हैं।

हमारे नये टेलीफोन नम्बर

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के विले पार्स (बम्बई) स्थित केन्द्रीय कार्यालय के टेलीफोन नम्बर बदल गये हैं। नये टेलीफोन नम्बर इस प्रकार हैं. ५७१३२४, ५७१३२५, ५७१३२६, ५७१३२७, ५७१३२८ और ५७१३२९।

खादी आन्दोलन का बुनियादी विचार

कमलेश्वरानन्द पाण्डेय

खादी गांधीजी के रचनात्मक कार्य का मुख्य आधार थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि खादी को अपने बुनियादी विचार से च्युत कर मात्र व्यापार की वस्तु नहीं बना देना चाहिए।

खादी शब्द का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका गांधीजी के प्रवचनों के सकलन को पढ़ कर ही पता चलता है। बापू दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर एक बार रेवाशकर-भाई के साथ बम्बई में स्वदेशी स्टोर देखने गये। सारी दुकान देखने के बाद बोले कि “इस स्टोर को सच्चे अर्थ में मैं स्वदेशी स्टोर नहीं कहूँगा। यह तो बिलायती स्टोर ही है।” रेवाशकरभाई आश्चर्यान्वित थे, क्योंकि स्टोर में कोई भी तो चीज ऐसी नहीं थी जिसे विदेशी कहा जाय। समस्त सग्रह स्वदेशी वस्तुओं का था। गांधीजी ने उनकी परेशानी को समझ कर अपना अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा था—“यह कपड़ा करघे से निकाला हुआ तो है पर इसे स्वदेशी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि प्रयोग होनेवाला सूत भी हाथ कता न हो। स्वराज्य की पहली सीढ़ी चरखा ही तो है, करघे का नम्बर तो बाद में आता है।” तब तक स्वदेशी का नाम खादी नहीं पड़ा था। स्वदेशी की व्याख्या करते हुए गांधीजी ने कहा था कि “ऐसा उद्योग जिसमें शोषण और प्रतियोगिता की भावना समाविष्ट न हो, अपितु, जो देश के असह्य गाँवों में स्वालम्बन के प्रति सच्ची निष्ठा उत्पन्न कर सके तथा आदान-प्रदान की भावना को प्रोत्साहित करे, वही उद्योग स्वदेशी की कल्पना को मूर्तिमान कर सकेगा।”

प्रारम्भ

सन् १९१५ में गांधीजी ने कोचरब आश्रम की स्थापना की। उससे पूर्व स्वदेशी की मीमांसा जन साधारण के समक्ष के बाहर थी। स्वदेशी को प्रारम्भ में केवल राजनैतिक महत्व दिया गया। आश्रम में तब कपड़ा

बुनने के करघे लगाये गये थे, पर उन पर सूत विदेशी मिलो का ही बुना जाता था। गांधीजी सूत के लिए मिलो का आधार लेने में मर्मतिक पीड़ा अनुभव करते थे। उनकी पीड़ा का समाधान निकाला गया बहन जवेरी ने। अहमदाबाद से ३९ मील दूर बीजापुर में उन्होंने एक चरखे का पता लगाया और गांधीजी को बताया। बापू के कण्ठ से आल्हाद मिश्रित स्वर गूज उठा। वे बोले “स्वराज्य के दर्शन हो गये।” शीघ्र ही सारे देश में चरखा स्वराज्य का मूर्तिमान स्वरूप बन कर प्रचारित होने लगा और उसके सूत से जो कपड़ा बुना जाने लगा, उसे बापू ने खादी का नाम दिया। सन् १९१९ में जब बहिष्कार आन्दोलन चला तो बापू ने बहिष्कार के लिए राष्ट्र को सशक्त पाया। उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा, “बहिष्कार अब एक भावुक जिद्द नहीं रही, मैनचेस्टर की मिलो की मुनाफाखोरी को रोकने के लिए चरखे के स्वरूप में मिलो का आधिपत्य मेरे हाथ में आ गया है।” बापू ने देश से खादी व्रत लेने का आग्रह किया और तब से खादी के धागे में स्वराज्य का नाम गूजने लग गया।

■ आज खादी घुटनों के बल रेगती हुई किशोरावस्था को प्राप्त हो गयी है और जब कभी खादी की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है तो उस पर यौवन भी आ जाता है। यह प्रगति का सूचक है। पर प्रश्न उठता है कि बापू व्यापारी थे अथवा एक दार्शनिक या सुधारक। उन्होंने खादी उद्योग अग्रजों के प्रति द्वेष अथवा स्पर्धा के कारण ही चलाने की प्रेरणा दी थी अथवा इस उद्योग के पीछे उनकी कुछ मान्यताएँ थीं?

इस प्रश्न का उत्तर शायद मैं एक उदाहरण देकर

स्पष्ट कर सकूँ। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के समय खादी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अकस्मात् उनकी दृष्टि एक सूत कातनेवाली अंधी महिला पर पड़ी। अंधी हो कर भी वह बड़ी खूबी से सूत कात रही थी। श्री विठ्ठलदास जेराजाणी, स्वर्गीय मदनमोहन मालवीय के साथ थे। विनोद ने उन्होंने चाकू से चरखे की माला काट दी। अंधी कत्तिन ने चरखे पर हाथ फेर कर टूटी हुई माला को पकड़ लिया और साड़ी के एक छोर में बंधी नयी माला चढ़ा कर फिर से कातने लगी। मालवीयजी के मुह से सहज ही निकल पड़ा, “खादी कार्य के लिए पूजी एकत्रित करनी हो तो मैं इस बहन को साथ ले कर घूमगा। मुझे विश्वास है कि देश ऐसे लोगों की माँग पूरी करेगा।”

इसी प्रकार तिरुपुर (मद्रास राज्य) के पास तिरुचे-गोडू नामक खादी केन्द्र का संचालन उन दिनों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी करते थे। वे उन दिनों **यंग इंडिया** के सम्पादक भी थे। एक दिन एक कत्तिन अपनी मजदूरी के पैसे माँगने आयी तो केन्द्र के अधिकारियों ने उसे दूसरे सप्ताह आने को कहा, क्योंकि उनके पास तब मजदूरी देने को पैसे नहीं थे। कत्तिन ने राजाजी से शिकायत कर दी, तो राजाजी ने अधिकारियों की ओर सकेत करते हुए कहा, “खादी का आविष्कार तो हुआ ही इसलिए है कि उसके द्वारा हम सबकी सुविधा देखे, पर ये महाशय खादी केन्द्र में भी व्यक्तिगत सुविधा देखते जा रहे हैं।” कितना कटु व्यंग था राजाजी की बात में। कितने सरल शब्दों में उन्होंने खादी के लक्ष्य को सामने रख दिया था!

आर्थिक बुराईयों का हल

स्पष्ट है कि खादी के कार्यक्रम के पीछे व्यापारिक लक्ष्य न कभी था न होना चाहिए। जिस राम-राज्य की गांधीजी ने कल्पना की थी, खादी उद्योग को उन्होंने उस राज्य के आर्थिक स्तम्भ की मान्यता दी थी। सन् १९३३-३४ की बात होगी। उन्होंने एक पत्र में अपना सदेश देते हुए लिखा था, “जिनके दिल में सात लाख देहातो मे बसनेवाले आधे भूखे-नंगे करोड़ों लोगों के प्रति रक्ती भर भी दया हो तो वे चरखा और खादी से द्वेष

कैसे कर सकते हैं। गांधीजी खादी और कुटीर उद्योगों को ही राष्ट्र का आर्थिक सूत्र समझते थे। विदेशी सत्ता का उन्मूलन यदि उनका राजनैतिक कार्यक्रम था, तो खादी उनके रचनात्मक कार्यों की पहली श्रृंखला थी। राजनैतिक कार्यक्रमों में ही लीन रह कर रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा करना वे एक नैतिक अपराध समझते थे। खादी का विकास उनके लिए नैतिक कर्तव्य की पूर्ति थी। खादी की मीमांसा को जनता के समक्ष रखते हुए उन्होंने १९३५ में अपने एक लेख में विचार प्रगट किया कि “कितने की खादी बिकी, यह मेरी दृष्टि से बड़ी बात नहीं, लेकिन जो खादी बिकी वह खरीदारों ने ग्रामोन्नति की भावना से खरीदी तो उस भावना का मेरे मन में अधिक मूल्य है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम खादी के दीवाने बने, खादी का इष्ट समझे।”

गांधीजी ने कभी भी व्यापारिक दृष्टिकोण से बिक्री के लिए मान्यता नहीं दी। सन् १९३५ में खादी की बिक्री ५० लाख तक पहुँच चुकी थी। अधिकांश कार्य-कर्त्ताओं को इस बात का बड़ा अभिमान था। पर गांधीजी ने उन्हें तब भी खूब प्रताड़ना दी। **हरिजन** में प्रकाशित अपने एक लेख के जरिये उन्होंने इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया। दिनांक २६ अक्तूबर १९३४ को स्वर्गीय राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में एक स्मरणीय अधिवेशन हुआ। रचनात्मक कार्यक्रमों में तब तक केवल खादी पर ही ध्यान दिया गया था। ऐसे उद्योग, जिनके विकास के लिए गाँव में पर्याप्त क्षेत्र या तो लुप्त हो चुके थे अथवा उपेक्षित पड़े थे उन्हें पुनर्जीवित करने की दिशा में चर्खा सघ की भाँति ग्रामोद्योग सघ की स्थापना का प्रस्ताव उस अधिवेशन में स्वीकृत हुआ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद

सन् १९४७ तक खादी एवम् अन्य ग्रामोद्योग किसी न किसी प्रकार चलते रहे। स्वराज्य-प्राप्ति पर स्वाभाविक रूप से अनेकों के मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि अब इन उद्योगों की क्या रूपरेखा होगी। स्पष्ट था कि कुटीर उद्योग उत्पादन की दृष्टि से मशीनों की प्रति-

योगिता नहीं कर सकते और कुटीर उद्योगों पर अवलम्बित होने का स्पष्ट अर्थ था कोरी भावुकता में बह कर उत्पादन की क्षति करना। तभी बापू ने एक प्रकाश की किरण फेंकी। उन्होंने जनता को खादी को अहिंसा और त्याग के प्रतीक के रूप में देखने की प्रेरणा दी। 'खादी को व्यापार के तराजू' में तोलनेवाले भ्रातृ कार्यकर्त्ताओं को फिर से नैतिक बल मिला और फलस्वरूप १३ मार्च १९४८ को सेवाग्राम में देश भर के रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। उक्त सम्मेलन में गांधीजी की प्रेरणा से संचालित समस्त रचनात्मक संस्थाओं का एकीकरण कर सर्व सेवा सघ नामक संस्था की स्थापना की गयी। राज्य सरकारों ने भी खादी के विकास में रुचि लेनी आरम्भ की, पर तब सब को यही लगा कि मिलो की प्रतियोगिता में कहीं खादी उद्योग नष्ट न हो जाय। अतएव खादी के उत्पादन पर ही विशेष ध्यान रहा। बिक्री की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिणाम-स्वरूप १९५२ में ९० लाख रुपये की खादी जमा हो गयी। सरकार ने तभी १९५३ में खादी के काम को संगठित करने के लिए अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना की। मण्डल स्थापित होने से पूर्व चरखा सघ की शाखाओं के जरिये लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की खादी प्रति वर्ष विकती थी।

आज खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के निर्देशन में खादी व अन्य ग्रामोद्योगों के विकास की भी कई योजनाओं पर अमल हो रहा है। खादी आज पर्याप्त विकास

पर है— न केवल उत्पादन की दृष्टि से अपितु इस दृष्टि से भी कि सर्व माधारण जनता उसे अपना रही है। माँग और पूर्ति दोनों में पर्याप्त मतुलन है। अम्बर चरखे के आविष्कार ने एक ओर सूत के उत्पादन में वृद्धि की तो दूसरी ओर उसके कारण खादी के वस्त्रों में नयी कलात्मक डिजाइनें भी देखने को मिली। प्रारम्भ में खादी केवल पहनने के वस्त्रों के रूप में ही प्रयोग में लायी जाती थी, लेकिन आज प्रायः सभी कामों में—जैसे पर्दे आदि—इसका उपभोग होता है। खादी आज एक अच्छी खासी मात्रा में विदेशों को भी भेजी जाने लगी है। खादी के उत्पादन को उपभोक्ता की रुचि के साथ जोड़ कर अर्थात् उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन करके खादी का आन्तरिक उपभोग बढ़ाया जा सकता है। ऐसे उदाहरण हैं कि खादी की भाँता और उसके विशेष आकर्षण के कारण वे व्यक्ति भी इसकी ओर आकर्षित हुए हैं, जो आदतन खद्दरधारी नहीं थे।

तथापि, खादी की अंतिम सफलता इस बात पर निहित है कि उसके साथ कर्मगारों की धारा प्रवाहित हो, परस्पर दिल जुड़ते चले जाय, भ्रातृत्व भावना बढ़े, ऊँच-नीच का भेद-भाव मिटे। वह ऐसे गुणोवाले समाज की, जीवन दर्शन की तथा आचार-विचार की प्रतीक हो। असल में ये ही तो वे भावनाएँ व विचार हैं, जो राष्ट्रपिता महान्मा गांधी प्रत्यक्ष करना चाहते थे।

मालीगॉव (असम) : ५ सितम्बर १९६३

ग्रामीण विकास, अर्थ और समाज शास्त्र सम्बन्धी सोद्देश्य और शिक्षाप्रद लेखों पर सम्पादक द्वारा सहर्ष विचार किया जायेगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की अविकसित अर्थ-व्यवस्था

इस्तेफा हुसैन

उच्च आबादी घनत्व और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ हैं। राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने चार वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के बस्ती जिले का यथा तथ्य अध्ययन करने के बाद इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया था कि बाढ़ पर काबू पाया जाय, सिंचाई-सुविधाओं और पीने के पानी की पूर्ति की जाय, सड़कें बनायी जाय, भूमि-उपयोग पद्धति में सुधार किया जाय, आदि। ये सिफारिशें पूर्वी क्षेत्र के अन्य जिलों पर भी वैसे ही लागू होती हैं, जैसे कि बस्ती जिले पर।

उत्तर प्रदेश को समग्र दृष्टि से देखने पर वह प्रगति के प्रमुख सूचकों में अखिल भारतीय औसत से पीछे है। राष्ट्र रूपी वस्त्र में यह एक फटी हुई जेब है। आय और आर्थिक तथा सामाजिक व्यय के मामले में उत्तर प्रदेश शेष भारत से काफी पीछे है। देश के सभी क्षेत्रों का

समान विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य में परिव्यय-स्तर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तालिका १ और २ से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है।

तालिका १

राज्यों में प्रति व्यक्ति परिव्यय तृतीय योजना

राज्य	तृतीय योजना में राज्य का हिस्सा (करोड़ रुपये में)	१९६१ में राज्य की आबादी (करोड़ में)	प्रति व्यक्ति परिव्यय (रुपये में)
जम्मू और कश्मीर	७५	०.३६	२०८.३३
राजस्थान	२३६	२.०१	११७.४१
पंजाब	२३१	२.०३	११३.९९
मैसूर	२५०	२.३५	१०६.३८
महाराष्ट्र } गुजरात }	३९० } २३५ }	६.०१	१०३.९९
असम	१२०	१.१९	१००.८४
केरल	१७०	१.६९	१००.५९
मध्य प्रदेश	३००	३.२४	९२.५९
उड़ीसा	१६०	१.७६	९०.९१
मद्रास	२९१	३.३७	८६.३५
आंध्र प्रदेश	३०५	३.६०	८४.७२
बिहार	३३७	४.६५	७२.४७
पश्चिम बंगाल	२५०	३.५०	७१.४३
उत्तर प्रदेश	४९७	७.३८	६७.३४

तालिका २

राज्यों की योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय १९५१-६१

राज्य	मार्च १९५६ में आबादी (करोड़ में)	प्रथम योजना में प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये में)	द्वितीय योजना में प्रति व्यक्ति व्यय (रु में)
पंजाब	१ ७७	९२ ०९	८३ ६२
जम्मू और कश्मीर	० ३४	३८ २३	७३ ५१
उड़ीसा	१ ५८	५३ ७९	६५ १७
बम्बई	५ ३६	४१ ७१	५७ ००
मैसूर	२० १४	४३ ९२	५५ ६१
पश्चिम बंगाल	२ ९९	५१ ५०	५३ ७९
राजस्थान	१ ७८	३७ ६५	५२ ३९
आंध्र प्रदेश	३ ३४	३२ ३३	५२ ३५
मध्य प्रदेश	२ ८७	३२ ७५	५० ५२
केरल	१ ५१	२९ १३	५० ३३
मद्रास	३ १९	२६ ६४	५० ००
असम	१ ०२	२७ ४५	४८ ४९
बिहार	४ २१	२४ ४१	३९ ४२
उत्तर प्रदेश	६ ८०	२४ २२	३३ ५३

फिर, स्वयम् राज्य के भीतर भी कुछ अवनत इलाके हैं। आयोजन के उद्देश्य से मोटे तौर पर तीन क्षेत्र विशेष समस्याओंवाले क्षेत्रों के रूप में माने गये हैं। ये तीन अविकसित यानी पिछड़े हुए इलाके हैं (१) पूर्वी जिले, (२) बुन्देलखण्ड, और (३) पहाड़ी जिले।

पूर्वी जिले

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी के जिले आते हैं। इन जिलों में आबादी घनत्व बहुत अधिक है, लोग दो जून रोटी भर

खा सकने की स्थिति में है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है (देश में एक निम्नतम स्तर), आये दिन की बाढ़ और सूखे से कमी की अवस्थाएँ बनी रहनी हैं, प्राकृतिक साधन-स्रोतों की अत्यधिक कमी है और सामान्यतः समूचा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है—खास कर यातायात तथा उद्योग की दृष्टि से।

केरल और पश्चिम बंगाल के बाद आबादी घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का स्थान है। खेती पर निर्भरता तो इन जिलों में पश्चिम बंगाल से भी अधिक है। तिस पर भी, पश्चिम बंगाल के विपरीत इन जिलों की भूमि उपजाऊ नहीं है, वर्षा का होना अनिश्चित है और वर्ष की सामान्य स्थिति में भी प्रति एकड़ उपज कम है।

कृषि पर निर्भरता

पूर्वी जिलों की अर्थ-व्यवस्था अनिवार्य रूप से ही कृषि-प्रधान है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की ६५ प्रति शत जन-संख्या के विपरीत पूर्वी जिलों की ८५ प्रति शत आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है। लखनऊ और मेरठ जिलों को छोड़ कर—जिनकी आबादी उनके आकार तथा लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद शहरों से प्रभावित है—सर्वाधिक घनी आबादी राज्य के पूर्वी छोर के जिले बलिया की है। आबादी के अत्यधिक घनत्व और कृषि पर निर्भरता ने इन पूर्वी जिलों में बड़ी गंभीर उलझने खड़ी कर दी है। इन कारकों से खेतों का आकर कम होने लगता है। एक उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट करना ठीक होगा। गोरखपुर प्रमण्डल में सकल कृषि क्षेत्र ४७ लाख एकड़ है। गोरखपुर प्रमण्डल की आबादी १९५१ में ८८ लाख ३० हजार थी। इसका मतलब है प्रति व्यक्ति ० ५३ एकड़ भूमि जोती जाती है। कम कृषि-उत्पादन, केवल १२ ७ प्रति शत क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएँ होने और मानसून की अनिश्चितता के कारण पूर्वी जिलों के निवासी बड़ी मुश्किल से खेती से अपना गुज़र-बसर कर पाते हैं।

इसलिए यह बहुत ही वाछनीय है कि इन जिलों के पूर्ण अथवा अर्ध-बेकार और कृषि पर ही अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर करनेवाले व्यक्तियों को उद्योग, वाणिज्य अथवा व्यवसाय में लगाया जाय।

‘राप्रआअप’ की सिफारिशें

लगभग चार वर्ष पूर्व राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (नेशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च) ने राज्य के एक पूर्वी जिले—बस्ती—का यथा तथ्य अध्ययन किया था। उस वक्ता उसने सिफारिश की थी कि

“ बस्ती में आर्थिक विकास की सम्भाव्यताएँ देश के अन्य अनेक भागों से कोई विशेष भिन्न नहीं हैं। वे या तो बस्ती में अधिक स्पष्ट हैं अथवा फिर उन्होंने जिले को अन्य क्षेत्रों से भिन्न रूप में प्रभावित किया है।

“ प्रधान समस्याएँ भौतिक हैं। अन्य किसी उल्लेखनीय दीर्घ-कालीन विकास का परिणाम देनेवाले कदम के उतारों से पहले इन समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए। ऐसे क्षेत्र में बारबार बाढ़ का आना—जोकि उसे सहन करने की स्थिति में नहीं है—न केवल महान क्षति पहुँचाता है, बल्कि निवासियों को अपने स्वयम् के विकास के लिए कोई कदम उठाने की प्रेरणा के सम्बन्ध में अनुत्साहित भी कर देता है। इसी प्रकार फमल सुधार और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सिचाई और पीने के पानी की व्यवस्था करना परमावश्यक है। सड़को सम्बन्धी तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएँ प्रदान करनी ही चाहिए, ताकि विकास के लिए संचार, शिक्षा, बिक्री-व्यवस्था जैसी बुनियादी बातें सम्भव बन पड़ें।

“इन भौतिक उपायों के साथ ही साथ घरेलू स्थिति में भी नवीनीकरण आना ही चाहिए। भूमि-उपयोग के तरीके में सुधार होना ही चाहिए। क्षेत्र के कृषि उत्पादनों के तरीके में सुधार लाना ही चाहिए। क्षेत्र के कृषि उत्पादनों का प्रशोधन करने के जरिये (चूकी अन्य कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिस पर

विकास आधारित किया जा सके) अधिकतम रोजगारी प्राप्त करनी ही चाहिए।

“ये बुनियादी परिवर्तन लाने में सहूलियत हो, इसके लिए सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं का समग्र विस्तार किया ही जाना चाहिए। चूँकि इस प्रकार की सुविधाओं के लिए विनियोजन करने में क्षेत्र बहुत ही गरीब है, इसलिए उनका बाहर से प्रदान किया जाना आवश्यक है—लेकिन ये सुविधाएँ इस ढंग से प्रदान की जानी चाहिए कि स्थानीय निवासियों की मान-मर्यादा बनी रहे और उनके भविष्य पर उनका स्वयम् का नियंत्रण सुनिश्चित बने।

“ये सब सुधार होने के बाद भी यह शकास्पद ही है कि वर्तमान विकास-दर के अनुसार बस्ती जिला १९७१ में अनुमानित जनसंख्या की कभी मदद कर भी सकता है। इसलिए जिले के क्षीण साधन-स्रोतों पर लोगों का निर्भर रहना कम करने के लिए कोई उपाय करना ही चाहिए।”

विशेष ध्यान देना आवश्यक

बस्ती जिले के लिए जो कुछ कहा गया है वह प्रायः सभी पूर्वी जिलों के लिए सच है। जब तक विकास कार्यक्रम के पीछे पूँजी आयात करने की स्पष्ट नीति न हो तब तक इन जिलों की गिरती हुई अवस्था को सुधारने के लिए कोई छाप डालना मुश्किल है। राज्य के सभी क्षेत्रों का एकरूप विकास सुनिश्चित करने के लिए परिव्यय-स्तर काफी बढ़ाना पड़ेगा और विनियोजन के किसी भिन्न तरीके का अनुसरण करना पड़ेगा। ‘सम्मान’ व्यवहार से ही पूर्वी जिले राज्य के शेष भाग के साथ कदम मिला कर नहीं चल सकेगे।

इस क्षेत्र के कृषि-सुधार के लिए कदम उठाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सिचाई सुविधाएँ प्रदान करने और बाढ़ पर नियंत्रण करने का बहुत बड़ा महत्व है। बाढ़-नियंत्रण के सम्बन्ध में अब तक केवल अन्यमनस्क कदम ही उठाये गये हैं। इसके अलावा लघु सिचाई

योजनाओं के रूप में प्राप्त सुविधाओं के नियम कुछ ऐसे हैं कि वे व्यक्ति ये सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्हें इनकी वास्तव में जरूरत है।

पूर्वी जिलों में, जिनकी ८० प्रति शत आबादी कृषि पर निर्भर करती है, कृषि विकास की कितनी अधिक आवश्यकता है, इस पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं। इस क्षेत्र में लोगों की आर्थिक कठिनाइयों कम करने की किसी भी योजना में मुख्याधार कृषि ही होना चाहिए। चूंकि इन क्षेत्रों में खेत बहुत छोटे-छोटे होते हैं और चूंकी राज्य के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में प्रति एकड़ उपज बहुत कम है, इसलिए कृषि पद्धति आवश्यक रूप से ही सघन बनानी पड़ेगी। चूंकी इन क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन के प्रत्येक कतरे पर खेती की जाने लगी है, इसलिए ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। सघन कृषि के लिए उर्वरकों और खाद की पूर्ति तथा सिंचाई की व्यवस्था करने एवं बाढ़ पर काबू पाने का सर्वाधिक महत्व है। चूंकि गुप्त बेरोजगारी बहुत है, इसलिए लघु सिंचाई व्यवस्था का विशेष महत्व है। लघु सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में राज्य की सिंचाई व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बनाने व उस पर विशेष ध्यान दिये जाने की भी आवश्यकता है। बोरिंग करते हुए पक्के कुए खोदने और उनमें उन्नत प्रकार के रैहट लगाने के काम को सघन रूप देना होगा।

पशुओं पर अन्वेषण

पूर्वी जिलों की अर्थ-व्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि राज्य के करीब २५ प्रति शत भैंस-भैंसे और ४० प्रति शत अन्य मवेशी इन्हीं जिलों में हैं। पशुओं की अधिक सख्या और छोटे-छोटे खेतों तथा विपरीत जलवायु सम्बन्धी अवस्थाओं के कारण चारे की कमी होने की वजह से रफ़ता-रफ़ता पशु-धन की अवस्था खराब हो गयी है। पूर्वी जिलों में मवेशियों की नस्ले समाप्त न हो जाये, इसके लिए इन जिलों की अवस्थाओं के अन्तर्गत पशुओं को चराने, उनके प्रजनन

आदि के सम्बन्ध में कोई विशेष अनुसंधान कार्य हाथ में लेना आवश्यक है। किन्ती एक पूर्वी जिले में एक छोटा-सा मवेशी प्रजनन कृषि-सह-प्रयोग केंद्र खोलना परमावश्यक है, जहाँ स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार का अध्ययन और प्रयोग किया जा सके, ताकि प्राप्त परिणाम आम-पाम के अन्य जिलों में प्रयुक्त किये जा सकें। मुर्गी-पालन, भेड़-बकरी-पालन, शुअर-पालन, मत्स्य-पालन आदि कुछ अन्य मद हैं जिनका विकास कार्य हाथ में लिया जा सकता है।

औद्योगिकरण

मात्र सघन कृषि ही पर्याप्त नहीं है। भूमि पर दबाव कम करने के लिए किसी हद तक लोगों को बाहर जाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यह एक सर्व विदित तथ्य है कि पूर्वी जिलों की अत्यधिक गरीबी ने लोगों को अपने जीविकोपार्जन के लिए देश के कोने-कोने और यहां तक कि विदेशों तक जाने को बाध्य किया है। गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिलों के हजारों व्यक्ति बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े शहरों में छोटा-मोटा व्यापार व छिट-पुट काम करते हैं। आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तथा जौनपुर ऐसे स्थान हैं जहां के व्यक्ति व्यापार अथवा सेवा में भाग्य की परीक्षा करने के लिए रगून, मलाया, सिंगापुर, वियतनाम और हांग कांग तक चले गये हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए देश के अन्दर और बाहर—जहां स्थानान्तरण की गुंजाइश हो—लोगों को भेजने के लिए आयोजित स्थानान्तरण की नीति का अनुसरण उपयुक्त होगा। इससे इन क्षेत्रों में स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर बिना किसी क्रम के स्थानान्तरण की जो प्रवृत्ति है वह नियमित हो सकेगी। आयोजित स्थानान्तरण से आगे चल कर इन जिलों में आबादी का जो दबाव है, उसमें भी राहत मिलेगी।

पूर्वी जिलों में भीषण पूर्ण और अर्ध-बेरोजगारी की समस्या हल करने तथा सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दृष्टि से औद्योगिक विकास करना एक तात्कालिक

आवश्यकता है। इलाहाबाद और मिर्जापुर को छोड़ कर तेरह जिलों में १९५७ में ५४ पञ्जीकृत कारखाने थे जिनमें से प्रत्येक में औसतन १०० या उससे कुछ अधिक और सब में औसतन ३०,००० से कम व्यक्ति रोजाना काम करते थे। (इस सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ यह बताया जा सकता है कि उसी वर्ष मेरठ जिले में ३४ कारखाने थे, जिनमें औसतन १६,७०० कामगार काम करते थे।) मौजूदा ीर्थ स्तरीय उद्योगों का विस्तार कार्य और नये उद्योग शुरू करने का काम हाथ में लेना पड़ेगा। कृषि करने का सघन तरीका अपना कर इन पूर्वी जिलों में गन्ना-उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र में चीनी के कुछ नये कारखाने खोले जा सकते हैं। फिलहाल देवरिया और गोरखपुर में एक-एक आसवनशालाएँ (डिस्टीलरी) हैं। ये आसवनशालाएँ उपलब्ध छोएँ का इस्तेमाल कर लेती हैं। पूर्वी जिलों में चीनी के नये कारखाने खुलने से और अधिक छोएँ की प्राप्ति हो सकेगी, जिससे एक या दो आसवनशालाएँ और शुरू की जा सकती हैं। शक्ति मध्यसार (पावर अलकोहल) की प्राप्ति होने की वजह से ऐसेटिक एसिड, ईथल ऐसेटेट, बटल अलकोहल आदि जैसे शक्ति मध्यसार के 'आधार' पर चलनेवाले उद्योगों का क्षेत्र में विकास किया जा सकता है।

उद्योगपुरियां

इस क्षेत्र में खोई-जिसका फिलहाल चीनी के कारखानों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है— का इस्तेमाल करते हुए कागज मिले भी स्थापित की जा सकती हैं। चीनी मिलों में कोयले से काम देनेवाले बॉयलर की स्थापना करके खोई बचायी जा सकती है। कागज मिल को कास्टिक सोडा और क्लोराइड की जरूरत होती है। नमक के विद्युद्विच्छेदन (सोडियम क्लोराइड) से ये प्राप्त किये जा सकते हैं। कास्टिक सोडा और क्लोराइड बाहर से प्राप्त करने की अपेक्षा स्वयम् कागज मिल में अथवा अलग से कोई इकाई खोल कर राज्य में ही तैयार किये जा सकते हैं। चीनी मिलों में काम आनेवाले छूटे पुर्जे तैयार करने के लिए इस क्षेत्र

में यत्र बनानेवाली इजीनियरिंग इकाइया भी खोली जा सकती हैं। पम्प और बिजली की मोटरों का उत्पादन करनेवाली, क्षेत्र में खोली जा सकनेवाली दूसरी इकाई है।

वस्त्र, प्रसाधन सामग्री 'स्टेशनरी', साइकल व उसके पुर्जे, जूते, दवाइया, एल्यूमिनियम के बर्तन, काच के बर्तन, कप-प्लेट, उपस्कर, कृषि-औजार, रासायनिक उर्वरक आदि की मांग बढ़नेवाली है। जन-संख्या-वृद्धि, शिक्षा-विस्तार और क्रय-शक्ति की वृद्धि से निश्चय ही तैयार माल की मांग काफी बढ़ेगी। अतएव उक्त प्रकार की चीजे तैयार करने के लिए दीर्घ और मध्यम स्तर की इकाइया स्थापित की जा सकती हैं। मऊ (आजमगढ़ जिला), शाहगंज (जौनपुर जिला) या खलीलाबाद (बस्ती जिला) में, बुनकरों को उपयुक्त मात्रा में सूत की पूर्ति करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। भारतीय उर्वरक निगम (फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया) जापान के सहयोग से गोरखपुर में एक उर्वरक कारखाना खोल रहा है। यह कारखाना 'यूरिया' पैदा करेगा, जोकि अच्छी खेती के लिए एक आवश्यक उर्वरक है। इस कारखाने में लोगों को काम देने की महान क्षमता है। राज्य के इन भागों की जनता की अर्थ-व्यवस्था के लिए लघु तथा कूटीर उद्योग तो और भी महत्वपूर्ण हैं। ये उद्योग छोटे-छोटे किसानों की आय में पूरक बन सकते हैं। यह एक अच्छी बात है कि पूर्वी जिलों में उद्योगपुरियों की स्थापना हो रही है। लघु स्तरीय उद्योगों के विकास के लिए ये उद्योगपुरियाँ केन्द्र बिन्दुओं का काम करेगी।

रेलों का विस्तार

इन जिलों में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि चन्द कमियाँ हैं उन्हें पहले दूर किया जाय। ये हैं पर्याप्त परिवहन और सस्ती शक्ति का अभाव। पूर्वी जिलों में रेलों और सड़कों की कमी है। समूचे क्षेत्र में प्रायः छोटी लाइनें (मीटर गेज रेलवे) हैं, फलस्वरूप आयात-निर्यात का माल ऐसे वाहनान्तरण केन्द्रों के जरिये भेजना पड़ता है, जहाँ छोटी और बड़ी दोनों

लाइने मिलती हो। इसका परिणाम निकलता है देर होना, मालछाद व गोदामों आदि में चोरियों का होना और परिवहन खर्च का बढ़ना। इन अवस्थाओं में सुधार करने के लिए शाहगंज-दोहरीघाट की छोटी लाइन को बड़ी लाइन का रूप दिया जाना चाहिए। इससे काफी लोगों को काम भी मिलेगा। इस योजना में तुरन्त तथा दीर्घ-कालीन दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। देवरिया को खड़्डा, ठूठीबाड़ी और निचलोल होते हुए कप्तानगंज से जोड़नेवाली रेलवे लाइन का निर्माण करना दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है। इस लाइन के बन जाने से देवरिया और महाराजगंज के पूर्वोत्तर हिस्सों का एक तरह से द्वार मुक्त हो जायेगा। तथापि, यदि आवश्यक हो तो यह लाइन छोटी लाइन हो सकती है। दोहरीघाट, शाहजंजनवान, खलीलबाद, मेढवाल, नौतनवा तथा ठूठी-बाड़ी को परस्पर जोड़नेवाली एक अन्य उपयोगी रेलवे लाइन है। इससे गोरखपुर जिले की बासगाव तहसील और बस्ती जिले के कुछ हिस्सों का मार्ग खुलेगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अनेक नदियाँ बहती हैं। इलाहाबाद, पटना और फैजाबाद तक कम से कम दो नदियों—गंगा और घाघरा—में नदी यातायात का विकास किया जा सकता है। जिन जिलों से हो कर ये नदियाँ बहती हैं उनके वाणिज्य-व्यवसाय को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। यह बहुत सम्भव है कि इन नदियों में कुछ प्रशिक्षण देने की और उनकी खुदाई करने की आवश्यकता पड़े। ऐसा करना बाढ़ रोकने की दिशा में भी एक सहायक कदम होगा, जोकि अपने साथ

दुःख-दर्द और बर्बादी लाते हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के विकास के लिए सड़क विकास कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। इसमें कच्ची और पक्की सड़कें बनाने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगारी मिलने की बात भी आती है।

शक्ति की पूर्ति

आधुनिक युग में बिजली सभी प्रकार के प्राविधिक विकास की जनक है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यह बात विशेष रूप से लागू होती है, जिनमें कोयले और धात्विक तेल के साधन-स्रोत नहीं हैं। शक्ति परियोजनाएँ न केवल शक्ति जनन के लिए, बल्कि सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण के लिए भी अनिवार्य हैं। शक्ति-चालित उद्योगों के सफल संचालन के लिए सस्ती और प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऊर्जा की प्राप्ति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में राज्य के अन्य भागों की अपेक्षा ऊर्जा की दूरे ऊँची है। यह असमानता शीघ्र ही समाप्त की जानी चाहिए।

योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों—आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर और जौनपुर—की वर्तमान अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल भेजा था। अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन आयोग को दे दिया है। उसकी सिफारिशों उत्तर प्रदेश के सभी पन्द्रह पूर्वी जिलों में लागू की जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि सभी सिफारिशों पर तुरन्त अमल किया जाय।

गोरखपुर . २६ दिसम्बर १९६३

राज्य के कुल उत्पादन में दो-तिहाई हिस्सा कृषि और उद्योगों का है; बाकी वाणिज्य, परिवहन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं का। इन तृतीयक श्रेणी के कार्यों में १९५५-५६ में अन्दाजन १६ लाख अर्थात् कर्म-शक्ति के करीब २५ प्रति शत लोग रोजगारी पा रहे थे।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात : नेशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

ग्रामीण महाराष्ट्र में सहकार की प्रगति

प्रभाकर नाडकर्णी

महाराष्ट्र में औद्योगिक सहकार आन्दोलन अपेक्षाकृत नया है और उसका विस्तार अपर्याप्त। राज्य में औद्योगिक सहकारों की प्राप्त सफलताओं के मूल्यांकन से पता चलता है कि १९६१-६२ में उनकी प्रगति सतोपप्रद रूप से तीव्र नहीं रही। अतएव आन्दोलन को पुनर्गठित करने और उसे ठोस बनाने पर जोर देना पड़ेगा।

कृषिक सगठन के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। कृषिक वित्त को एक स्वरूप और व्यवस्था (अर्थात् सगठन प्रदान करने के लिए करीब २० हजार कृषि सहकारी समितियाँ भरसक प्रयत्न कर रही हैं। इनकी वित्तीय व्यवस्था २५ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और शीर्ष स्थल पर एक शीर्ष सहकारी बैंक करता है। वित्त का बिक्री-व्यवस्था के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए लगभग ४०० बिक्री सहकारी समितियाँ इन्हें सहायता पहुँचा रही हैं। समूचे राज्य में ६२१ सहकारी समितियाँ, सहकारी कृषि के क्षेत्र में जुटी हुई हैं। किसानों को अधिक अन्न उपजाने और ज्यादा जमीन पर खेती करने में समर्थ बनाने के लिए दीर्घ-कालीन ऋण देने की दिशा में २७ भूमि-विकास बैंक मूल्यवान् कार्य कर रहे हैं। किसानों के साथ अच्छा मल्लूक हो, इसके लिए उत्पादन का उनके सर्वोत्तम लाभ की दृष्टि से प्रशोधन करने के काम में २० चीनी मिलें, ३८ कपास ओटाई और दबाई मिलें तथा करीब ११७ प्रशोधन समितियाँ लगी हुई हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र में कृषकों द्वारा बनायी गयी तथा उनके लिए काम करनेवाली सहकारी समितियों में ११५ सिचाई समितियाँ व ७७० दुग्धोद्योग (डेरी) सहकारी समितियाँ और हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में भी अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, तथापि बड़े औचित्य के साथ यह कहा जा सकता है कि किसानों ने बड़े उत्साहपूर्वक सहकार अपनाया है। लेकिन कामगारों और कारीगरों के मामले में ऐसी बात नहीं है। उनके लिए अब भी सहकार एक नयी वस्तु ही है।

औद्योगिक सहकार आन्दोलन अपेक्षाकृत नया है, और इसका विस्तार अभी अपर्याप्त ही है। ग्राम और लघु स्तरीय उद्योगों का समुचित सगठन व प्रबन्ध किया जाय तो वे ग्रामीण समाज को पर्याप्त सख्या में रोजगारी प्रदान कर सकते हैं। इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं करता कि कृषि विकास के क्षेत्र के समान ही इस क्षेत्र में भी सगठन का सहकारी तरीका बहुत हितकर होगा। राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का श्रीगणेश करने के बाद स्थानीय विकास कार्यों के संचालन के लिए जिला परिषदों और पंचायत समितियों को उत्तरदायी बनाया गया है। कार्य विधि के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। चूँकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन से लोकमत का सक्रिय सम्बन्ध रहेगा, इसलिए सहकारी आन्दोलन में ग्राम, तालुका तथा जिला स्तर पर यह नये प्राण फूक सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में यदि ग्राम समाज के साधन-स्रोतों के अनुसार सुनियोजित कार्यक्रम बनाये जायें और ग्रामीणों को उनके कार्यान्वयन में उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जाय तो वहाँ पर विकास की गहान सम्भाव्यताएँ हैं। नीचे चन्द अनुच्छेदों से संक्षेप में इस बात का पता चलेगा कि ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में किये गये सहकारी प्रयासों की महाराष्ट्र में कितनी प्रगति हुई है।

महाराष्ट्र के सहकार आन्दोलन में ये सब आते हैं बुनकरों (ऊन, रेशम, खादी और शक्ति करघा कामगार) की उत्पादक सहकारी समितियाँ, सभी परम्परागत ग्राम, कुटीर और लघु-स्तरीय उद्योग—जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के

लिए हितकर है— वन्य श्रमिक और श्रमिक ठेकेदारी समितियाँ। इस शब्द में वैसा उद्योग या व्यापार भी आ जाता है जोकि कामगार सामूहिक स्वामित्व और प्रबन्ध के जरिये चलाते अथवा करते हैं। चूँकि सहकार आन्दोलन एक विकासशील वस्तु है, इसलिए उसकी परिभाषा आवश्यक रूप से ही लचीली होनी चाहिए।

स्वतंत्र विभाग

औद्योगिक सहकारो की १९४६-४७ में जो स्थिति थी उस पर एक दृष्टि डालना रुचिकर होगा। यहाँ यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि उसी वर्ष औद्योगिक सहकारी आन्दोलन के विकास हेतु एक अलग विभाग खोला गया था। भूतपूर्व बम्बई राज्य में ३० जून १९४७ को १७४ बुनकर समितियाँ, १२१ अन्य औद्योगिक सहकारी समितियाँ, तीन श्रमिक ठेकेदारी समितियाँ, १५ सघीय समितियाँ और एक राज्य शीर्ष मस्या थी। यहाँ १९४७ और १९६२ के बीच के तुलनात्मक आकड़े प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा

प्रभावक प्रतीत होंगे। किसी हद तक इसके लिए यह कहा जा सकता है कि सहकारी दृष्टि से विकसित क्षेत्र द्वि-भाषी बम्बई राज्य के विभाजन के फलस्वरूप वर्तमान गुजरात राज्य को मिला। चूँकि राज्य के मुगठिन क्षेत्रों में, खास कर औरंगाबाद प्रमण्डल और नागपुर प्रमण्डल के पूर्वी जिलों में, औद्योगिक सहकारी आन्दोलन के विस्तार की बहुत बड़ी गुजादश है, इसलिए आगामी वर्षों में, यह कमी दूर की जा सकती है। यद्यपि ३० जून १९६२ को पूरे होनेवाले १५ वर्षों में औद्योगिक सहकारी समितियों की कुल मस्या में प्रायः दस गुनी वृद्धि हुई है, तथापि उनकी कुल सदस्य-संख्या पाँच गुनी से कुछ अधिक और लेन-देन तीन-गुने से कुछ ज्यादा बढ़ा है। तुलनात्मक अध्ययन में औद्योगिक सहकार आन्दोलन की कमजोरियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सदस्य-संख्या में निश्चय ही समितियों की संख्या के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है, और लेन-देन (जैसा कि लेन-देन सम्बन्धी आकड़ों से प्रकट होता है) न तो समितियों की संख्या और न ही सदस्यों की संख्या के साथ बढ़

विवरण	३० ६ ४७	३० ६ ५८	३० ६ ६२
बुनकर समितियाँ	१७४	८४७	७११
अन्य औद्योगिक सहकार	१२४	२,०१३	२,५६२
सघीय समितियाँ (मय शीर्ष समिति के)	१५	२४	३२
सदस्य-संख्या	४०,०४५	२,५७,२८५	२,०७,७५२
कुल बिक्री	२,८२,६८,८२२	१०,६३,७७,०००	८,९४,७६,०००
संचालन पूँजी	४८,४८,३५४	७,४३,७४,५५०	७,२६,०९,०००

भूतपूर्व द्विभाषी बम्बई राज्य में ३०-६-१९४७ और ३०-६-१९६२ को समाप्त होनेवाले वर्षों के मध्य ३०-६-१९५८ को औद्योगिक सहकारो की स्थिति विषयक आकड़े प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य यह है कि उससे सामान्य पाठक को भी यह उपयोगी जानकारी मिल जाय कि राज्य पुनर्गठन के तुरन्त बाद बम्बई राज्य में औद्योगिक सहकारो की क्या स्थिति थी। इसके विपरीत महाराष्ट्र के १९६१-६२ के आकड़े कुछ कम

सका है।

तीन सोपान

यह आन्दोलन अपने जीवन के लगभग पन्द्रह वर्षों की अवधि में तीन सोपानों से होकर गुजरा है। प्रथम सोपान के दौरान इसने नियंत्रण के युद्धोत्तर-कालीन लाभो का फायदा उठाया। इसके बाद नियंत्रण हटा, जिससे समितियों को एक धक्का लगा और काफी समय तक उनकी प्रगति अवरुद्ध हो गयी। तीसरा सोपान

पुनरुद्धार या पुनर्जागरण का द्योतक है, जब समितियों ने जिन्हे पहले बका लगा था, अपने को दृढतापूर्वक जमाया और द्वितीय सोरान के दरमियान जो गतिहीनता आ गयी थी उसे दूर करने की कोशिश की। यही तृतीय सोपान—जिसके दौरान समितियाँ अपने खोये हुए आधार को पुन प्राप्त करती प्रतीत हो रही हैं— प्रस्तुत लेख का विषय है।

दिनांक ३०-६-१९६२ को औद्योगिक सहकारो की सख्या ३,५९० थी। उनके सदस्य २,०७,७५२ थे और कुल चुकता-पूजी १,७४,८१,००० रुपये। यदि अध्ययन की विषय-वस्तु संकुचित कर दी जाय और हम केवल परम्परागत पेशे अथवा काम-धंधे (बुनकर, श्रमिक, ठेकेदारी, वन्य श्रमिक तथा अन्य सभी सघीय समितियों को छोड़ कर) की औद्योगिक सहकारिताओं का ही अध्ययन करे तो देखते हैं कि उनकी सख्या २,०४८ और सदस्य-सख्या ७२,११९ कारीगर अथवा कामगार हैं, जिन्होंने अपनी समितियों की हिस्सा-पूजी में ८३,१९,००० रुपये दिये। इस आधार पर इन समितियों ने केन्द्रीय वित्तदात्री अभिकरणों से १,१०,३४,००० रुपये प्राप्त किये। सरकार अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा अथवा उनके तत्वावधान में उत्पादित माल की बिक्री से २,०५,४४,००० रुपये प्राप्त हुए। इन सबके फलस्वरूप ५४५ समितियों ने लाभ कमाया, ७८० घाटे में रही और ७३१ न नफे न नुकसान अर्थात् गतिहीनता की अवस्था में रही। उक्त स्थिति का और अधिक विश्लेषण करने पर हमें बहुआधार प्राप्त होगा जोकि उपचारात्मक कदम उठाने तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयोगी होगा।

निष्क्रिय समितियों का सवाल

सर्व प्रथम निष्क्रिय समितियों का समस्या-मूलक प्रश्न है, जिनकी सख्या समस्त चालू समितियों की एक-तिहाई से भी अधिक है। निष्क्रिय समितियाँ आन्दोलन में भार बनी हुई हैं और इस भार को कम करने के लिए उन्हें (१) पुन प्राणवान यानी क्रियाशील बनाते हुए अथवा

(२) यदि उन्हें फिर से क्रियाशील बनाने की कोई आशा या गुंजाइश न हो तो समाप्त अर्थात् बिल्कुल बन्द करते हुए प्रबल कदम उठाने पड़ेंगे। यद्यपि कोई भी प्रथम प्रकार के कदमों का समर्थन करेगा, तथापि द्वितीय कदम की उपयोगिता भी कम नहीं की जा सकती। अलाभदायक इकाइयों को समाप्त करने से ही आन्दोलन शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि निष्क्रिय समितियाँ सहकारिताओं के कोप में एक प्रकार के रिसाव हैं। निष्क्रिय समितियों पर सामयिक रूप से कुछ निश्चित खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है और पूजी अनावश्यक रूप से गैर-फायदेमन्द कामों में बन्द पड़ जाती हैं। इसके साथ ही साथ नये सगठन खड़े करते हुए और चन्द मामलों में तो उन्हें तरजीह देते हुए निष्क्रिय समितियों को पुन सक्रिय बनाने का एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेना पड़ सकता है। बहुत बड़ी सख्या में ऐसी समितियों की बजाय जो आनुपातिक रूप से कम लाभप्रद हों (और जिनमें से अनेक तो निष्क्रिय ही हों), कम सख्या में ही मही पर ऐसी समितियों की तरजीह दी जानी चाहिए जो लाभ कम रही हों, सदस्यों की उपयोगी सेवा कर रही हों तथा जिनमें अपना और विकास करने की क्षमता हो।

अन्तर्गतता घाटे में चलनेवाली समितियों में भी सुधार हो सकता है। प्रत्येक मामले का परीक्षण कर उसका उपचार खोजा जाना चाहिए। प्रशिक्षित कर्मचारी प्रदान करके (जोकि सहकार आन्दोलन की सबसे बड़ी सगठनात्मक कमी है), बाहर से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बुला कर, उपयुक्त कीमत पर कच्ची सामग्री की पूर्ति का प्रबन्ध करके, उपयुक्त बिक्री सगठन खड़ा करके, प्रचार-साधन का प्रयोग करके, नये साधन-मरजाम, यंत्रादि का समावेश कर घाटे में चलनेवाली समितियों को भी कमाई करनेवाली समितियों में बदला जा सकता है। इसलिए निष्क्रिय समितियों के बाद लगातार घाटा उठानेवाले सहकारो की अवस्था में सुधार करने का सवाल हाथ में लेना पड़ सकता है। लाभ कमानेवाली समितियों की स्थिति में और अधिक सुधार करना तीसरा कदम हो सकता है। हो सकता है कि उनमें भी

सभी बातें ठीक न हों। उदाहरण के लिए उनमें मित्त-व्ययीता लायी जा सकती है, माल का गुण सुधारा जा सकता है, सदस्यों को प्राप्त सेवा में बिना कोई कमी किये उनके सदस्य बढ़ाये जा सकते हैं, व्यवहृत प्रक्रियाओं में सुधार करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, ऊपरी खर्च कम किये जा सकते हैं, बिक्री-संगठन का विस्तार किया जा सकता है, अधिक वन-राशिका विनियोजन किया जा सकता है, आदि। ये सभी कदम साथ-साथ उठाने की आवश्यकता है।

राज्यों की औद्योगिक समितियों के वित्तीय कारोबार के सम्बन्ध में १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिए तुलनात्मक जानकारी आगे दो पृष्ठों पे दिये गये विवरण से प्राप्त की जा सकती है। पूर्व अल्लुछेद में वर्णित परम्परागत प्रकार की औद्योगिक सहकारी समितियों के तुलनात्मक आकड़े इस प्रकार हैं

समान रहा। इसका कारण यह हो सकता है कि उत्पादित माल बिक्री योग्य न हो। बेसी अतस्था में समितियों को ऐसे सामान का उत्पादन प्रारम्भ करना पड़ सकता है जो बिक्री की दृष्टि से अतुकुल हो।

केन्द्रीय वित्तदात्री अभिकरण

औद्योगिक सहकारियों को वित्त प्रदान करने के सम्बन्ध में यहाँ केन्द्रीय वित्तदात्री अभिकरणों का उल्लेख करना समीचीन होगा। केन्द्रीय वित्तदात्री अभिकरण प्रायः एक मात्र माध्यम है जिनके जरिये औद्योगिक सहकारियों को सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विविध विहित मण्डलों और आयोगों से वित्त प्रदान किया जाता है। नब्बे प्रति शत गम्हारी गारण्टी योग्य गियायती व्याज दर की योजनाओं के प्रारम्भ तथा १ जनवरी १९६३ से राज्य के सभी जिले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की योजना के

मद	१९६०-६१	१९६१-६२
समिति सख्या	१,९३३	२,०४८
सदस्यता	६६,०९८	७२,११९
टिस्सा पूजी (रु में)	६४,०१,०००	७७,९१,०००
उत्पादित माल (रु में)	१,५७,४६,०००	२,२९,६०,०००
बिक्री (रु में)	१,९०,४९,०००	२,०५,६६,०००
कुल उधार (रु में)	९०,९४,०००	१,१०,३६,०००
संचालन पूजी (रु में)	१,७०,२२,०००	२,२७,२०,०००

उपरोक्त आकड़ों से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आन्दोलन को मजबूत दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि वह प्रगति कर रहा है। तथापि, इस स्थिति पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, निष्क्रिय और घाटे में चलनेवाली समितियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समालोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। वर्ष १९६०-६१ में उत्पादित माल के मूल्य से बिके सामान की कीमत अधिक रही। उसके बादवाले वर्ष में स्थिति उल्टी रही। इससे कई सम्भावनाओं का इंगित मिलता है, जैसे या तो उत्पादन बढ़ा और बिक्री पहले जितनी ही रही या फिर बिक्री कम हुई और उत्पादन पहले के

अन्तर्गत आ जाने से किन्हीं हद तक जाचित्य के साथ यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक सहकारियों को पर्याप्त वित्त प्रदान करने का सवाल हल होने की स्थिति में है। इस सम्बन्ध में सरसरी तौर पर इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि बड़ी औद्योगिक सहकारियों को मध्य-कालीन वित्त प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी बैंक ने एक योजना बनायी है और औद्योगिक सहकारी प्रतिष्ठानों को दीर्घ-कालीन विस्त देने के लिए जीवन बीमा निगम ने इच्छा प्रकट की है। इसके साथ सहकारी वित्त के सस्यानीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई कही जा सकती है।

अपने विश्लेषण का विषय अब तक परम्परागत प्रकार की औद्योगिक सहकारिताओं तक सीमित रखते हुए भी कुछ अन्य प्रकार की समितियों (जोकि इस प्रकार के औद्योगिक सहकारों का एक मोटा वर्ग है) के सम्बन्ध में भी कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा। तेलघानी समितियों ने १९६१-६२ ने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन में कुछ गिरावट प्रदर्शित की है। उक्त काल में बिक्री के क्षेत्र में भी आनुपातिक गिरावट आयी है। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि भाण्डारीकरण वित्त योजना तब नहीं थी और वह परिमाण तथा क्षेत्र दोनों की दृष्टियों से सीमित थी। तथापि, इस योजना से तेलघानी उद्योग को काफी बढ़ावा मिलने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि यह तेलकार की तिलहनो के भावों में आनेवाली घट-बढ़ से रक्षा करने की कोशिश करती है, जोकि इस महत्वपूर्ण ग्राम उद्योग के पुनः फलने-फूलने में एक महान बाधा है। भाण्डारीकरण के निमित्त वित्त प्रदान करने सम्बन्धी योजना ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। इस सम्बन्ध में शोलापुर जिले में—जहाँ सर्व प्रथम यह योजना प्रारम्भ की गयी—उद्योग का जो विकास हुआ है उसका उदाहरण दिया जा सकता है। इस योजना के साथ ही गोदाम बनाने का कार्यक्रम चलाने से उद्योग को पुनःस्थापित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

सेवा सहकारी समितियाँ और बिक्री सहकारी समितियाँ तेल उत्पादन संस्थाओं के साथ सम्बन्ध जोड़ सकती हैं तथा तेलकारों की उत्पादक समितियों के संयोजन से ग्रामीण तेल उद्योग के विकास में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती हैं। वितरण व्यवस्था खड़ी करने में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ भी सहायक हो सकती हैं, जिससे रफ़ता-रफ़ता करके तैयार माल की आगत बढ़ेगी। अन्ततः सहकारी सम्बन्ध को—जिस पर अप्रैल १९६१ में नयी दिल्ली में सम्पन्न औद्योगिक सहकार विचार-गोष्ठी में जोर दिया गया था—यदि उक्त आधार पर ग्रामीण तेल उद्योग के विकास में प्रयुक्त किया जाय तो उसे ठोस रूप दिया जा सकता है। चूँकि तेल एक

प्रमुख पदार्थ है और गावों तथा शहरों दोनों में ही प्रत्येक व्यक्ति की ओर से उसकी बहुत बड़ी मांग है, इसलिए इस दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि इस उद्योग के विकास की बहुत बड़ी क्षमता है। यदि उत्पादन इतना बढ़ाया जाय कि उससे ऊपरी खर्च निकल सके तो घानी तेल मिल तेल की स्पर्धा में सीना तान कर खड़ा हो सकता है।

चर्मोद्योग

चर्म शोबन और चर्म सामग्री का उत्पादन करनेवाली समितियों की स्थिति आलोच्य दो वर्षों में प्रायः समान ही रही, यद्यपि सन्दर्भ के तौर पर यह कहना पड़ सकता है कि चर्म शोधक समितियों के उत्पादन और बिक्री में सुस्पष्ट गिरावट आयी है। इसके कारणों की जांच करनी पड़ सकती है। चर्म शोबन और चर्म सामग्री उत्पादन उद्योग व्यक्तिगत कौशल तथा कारीगरी के बूते पर ही जीवित रह कर पनप सकते हैं, क्योंकि संगठित क्षेत्र की ओर से स्पर्धा बहुत जबर्दस्त है। इन उद्योगों के कर्मियों को देहातो में पर्याप्त ग्राहक तभी मिल सकेंगे, जबकि वे अपने माल का गुण-स्तर बनाये रखें। वैसे तो यह सभी ग्रामीण कारीगरों के बारे में, पर चर्मकारों और चर्म शोधकों के सम्बन्ध में तो विशेष रूप से सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित बुरी सामाजिक अवस्थाएँ, शिक्षा का अभाव और ऊँच-नीच के भाव इस ग्राम उद्योग के सुव्यवस्थित व सुनियोजित विकास में बाधक रहे हैं।

सघन सामाजिक शिक्षा और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा शांति तथा धैर्यपूर्वक काम किये जाने पर ही चर्मकारों व चर्मशोधकों को इन सामाजिक बुराइयों से मुक्त किया जा सकता है एवम् उनमें ईमानदारी, निष्ठा आदि की भावनाएँ भरी जा सकती हैं, जोकि किसी भी सहकारी प्रयास की पूर्ववश्यकताएँ हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें सहकारी व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्त्ता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। यदि उद्योग का विकास सन्तोषप्रद रूप से हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त प्रदान करने के लिए इच्छा प्रदर्शित की है। अतः इनके विकास पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। मौजूदा औजारों का इस्तेमाल करने पर भी यदि सदैव ही

महाराष्ट्र में औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति १९६०-६१ और १९६१-६२

समितियों का प्रकार	समिति मलया		सदस्य सख्या		हिस्सा-पूजी (रु में)		उत्पादन (रु में)		बिक्री (रु में)	
	६०-६१	६१-६२	६०-६१	६१-६२	६०-६१	६१-६२	६०-६१	६१-६२	६०-६१	६१-६२
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
रगाई-छपाई	१३	१८	२८१	४६२	२०	३८	४४	३४	४२	४२
मधुमक्खी-पालन	५	७	७८५	१,०१७	१८	२६	१७	१२	११५	१०४
तेलघानी	२४६	२६५	६,३४७	६,६७७	६५४	६६३	६,४८०	५,०६४	७,९१७	५,३४९
हाथ धान कुटाई	६	६	३२३	३२३	७	७	१६३	२०	२०७	३८
बेत और बास	७७	८४	१,८१५	१,८५२	३८	३८	४८	६५	६८	९३
चर्म-शोधन	१४६	१४८	३,११५	३,२४९	१९६	२०७	६५४	५५५	६८०	५११
चर्मकारी	२७२	२७५	६,४६०	६,६६१	३१७	३४६	९०१	१,२२९	१,०७४	१,३८७
बढईगीरी और लोहारगीरी	१७७	१७४	३,९७०	४,७२८	२५८	२९७	८६६	१,००३	१,०१४	१,०९६
धातु कार्य	६८	७७	२,४६०	२,४६६	२२३	२६१	९७१	१,२७०	१,०२०	१,६९६
कुम्हारी व ईट-पथार्ड	२५०	२८०	८,४१६	९,३१२	३०७	३६७	६८८	१,०११	६७१	१,०६२
रेशा और रस्ती	१३०	१३९	३,८३७	४,२४५	७३	८०	११८	११३	१३०	११३
नीरा व ताड-गुड	६२	६८	१,७१२	१,८६८	९८	१०४	२८८	४१८	५९४	६६१
महिला समितियाँ	८१	८७	७,००७	७,२०३	१३८	१४७	७४८	५०३	९४७	६३९
विविध समितियाँ	४००	४००	१९,५७०	२२,०७८	४,०५६	५,२३०	३,६८०	६,३५८	६,५७६	७,८६९
योग	१,९३३	२,०४८	६६,०९८	७२,११०	६,६०१	७,७०९	१५,७६६	२२,०६०	१०,०६९	२०,५६६
बुनकर समितियाँ	७११	७२७	८५,२५५	८६,६९५	३,०८६	४,६६९	३५,१०६	३५,१०६	६०,५५२	६०,६९८
मधीय मस्थाएँ	३२	३४	६,२७०	७,३२९	१,०३८	३,०९६	१८,३५५	२३,८८२	२१,५०६	२८,८३६
वन्य श्रमिक समितियाँ	२५८	३१६	२५,८३६	३०,८६९	७६७	८८९				
श्रमिक ठेकेदारी समितियाँ	३७१	४६५	१७,३८६	२१,१३७	५४४	७५६				
योग	३,३०५	३,५९०	२,००,८४१	२,१५,९४९	१३,६१६	१६,०५६	६९,५९९	८१,९२६	८१,१०५	८९,६७६

अच्छे-भले रंगे चमड़े का उपयोग किया जायेंगे। समितियों में जूते व अन्य चर्मोद्योगी सामग्री बना सकती है। अच्छे रंगे चमड़े की पूर्ति के लिए चर्मकार समितियों को हो सकता है क्षेत्र की एक या अधिक चर्म शोधक समितियों के साथ समझौता करना पड़े।

प्रदत्त सहायता अपर्याप्त

जिला औद्योगिक सहकारी संघ अपने विप्रेक्षी केन्द्रों के जरिये चर्मोद्योगी सामग्री की विक्री को बढ़ावा दे सकते हैं। इन समितियों की सालाना उधार ५,१२,००० रुपये (चर्मशोधक समितियों की) और ८,७९,००० रुपये (चर्मकार समितियों की) है। इस प्रकार चर्मशोधक समितियों के मामले में प्रत्येक चर्म शोधक सदस्य को एक वर्ष में करीब १५० रुपये ही मिलते हैं। इस में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि कुल चर्मशोधक सहकारिताओं में लगभग ४६ प्रतिशत निष्क्रिय हैं। वास्तविक आवश्यकताओं की दृष्टि से प्रदत्त वित्त अपर्याप्त है, चर्म शोधक समितियों के मामले में प्रति सदस्य के हिसाब से उधार में कम से कम तीन गुनी वृद्धि करने का औचित्य है।

बढ़ड़यो, कुम्हारों तथा ईंट पाथनेवालों की समितियों की प्रगति यदि कुछ हुई है तो बहुत ही मामूली। भवन निर्माण उद्योग बहुत ही समृद्ध है। वह अपना सानी नहीं रखता। यह अपेक्षा करना समीचीन ही होगा कि बढ़ड़यो, कुम्हारों और ईंट पाथनेवालों की समितियों को भी इस समृद्धि का कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। भवन निर्माताओं को चौखटों तथा ईंटों की पूर्ति करने और बढ़ड़यो व ईंट पाथनेवालों की प्राथमिक समितियों को 'आर्डर' देते रहने का काम अपने हाथ में लेकर जिला औद्योगिक सहकारी संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यद्यत्तमाल जिला औद्योगिक सहकारी संघ ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। अन्य सबों को भी यदि वे वास्तव में अपनी इकाइयों के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं तो उक्त संघ का अनुकरण करना होगा।

नीरा और ताड़-गुड़ समितियों का अपना एक वर्ग है। उनकी समस्याएँ अपने ढंग की हैं और मध्यनिष्ठ

कानून में प्रभावित व्यक्तियों की सामाजिक अन्तर्थाओं में उनका वनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि रचनात्मक प्रयास किये जायें तो समितियों के पास ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी। जल्द ही इस बात की है कि निष्ठावान व ईमानदार कार्यकर्त्ता हो तथा भाण्डारीकरण और वितरण के लिए मुनियोजित एवम् अनुशामन पूर्ण तत्र हो। महिलाओं की समितियों का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवहार कुशलता और कौशल के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। यदि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित और उत्साही महिलाएँ इन समितियों की समन्वयाय सहायता के लिए आगे आकर अपनी प्रतिभा दिखायें तो न केवल वे महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से ऊपर उठाने का ही काम करेगी, बल्कि मध्यम वर्गीय महिलाओं को अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने का एक गंदावहारी स्रोत भी प्रदान करेगी।

पहले कहा जा चुका है कि सामाजिकीय आकड़े उन्नति अथवा अवनति के निश्चित निदर्शक नहीं हैं। ऊपर की मक्षित समालोचना में परिमाण की अपेक्षा गुण पर जोर दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि १९६०-६१ की तुलना में १९६१-६२ में प्रगति हुई है, पर वह धीमी रहने के साथ ही स्तरीय भी नहीं रही है। विस्तार की योजना बनाने में पूर्व आन्दोलन को पुनर्गठित और ठोस बनाने पर जोर देना पड़ेगा। यदि सहकार का फल सुस्पष्ट हो तो कामगार स्वयं उसकी ओर चले आयेगे। इस प्रकार आन्दोलन के ठोस बन जाने पर उसका विस्तार स्वतः होता जायेगा। चर्मकारों, चर्मशोधकों, बढ़ड़यो, ईंट पाथनेवालों, नीरा कार्यकर्त्ताओं तथा महिलाओं की समितियों के मामले में काफी पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जिला औद्योगिक सहकारी संघ प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। सब जिले के स्तर पर सहकारी विचार-प्रसार व प्रचार तथा अपनी समितियों द्वारा निर्मित माल को लोकप्रिय बनाने और उसका वितरण करने के प्रमुख केन्द्र होने चाहिए। ये अपनी इकाइयों को व्यवस्था यानी तौर-तरीके और योजनाएँ प्रदान कर सकते हैं तथा जिला स्तर पर औद्योगिक सहकारी आन्दोलन को मार्गदर्शन एवम् निर्देश दे सकते हैं।

पूना . १४ जून १९६३

तेल पेराई में सुधार

त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्ति

धानी के द्वारा तेल पेरने से जितना तेल प्राप्त होता है उसकी मात्रा में पेराई की प्रक्रिया को पूर्ण बना कर तथा स्वयम् धानी में सुधार करके वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण तेल उद्योग की प्रचलित प्रक्रियाओं में सुधार करने के किसी भी प्रकार के प्रयास में जिन बातों पर ध्यान देना वाछनीय है, उन पर प्रस्तुत लेख में विचार किया गया है।

पेराई में कम तेल की प्राप्ति ग्रामीण तेल उद्योग के सामने एक गम्भीर समस्या है। कमतेल-प्राप्ति में तेलकार को काफी कम आमदनी होती है। यही नहीं, इस कारण बाजार में अपना तेल प्रतिस्पर्धात्मक भाव पर बेचना भी उसके लिए मुश्किल हो गया है। उसकी तेल पेराई क्षमता का अग्रिकाश अश अनुपयोजित रहता है। इसमें उक्त कारक का भी हाथ है। तिलहनो से पूरा तेल निकाल लेने से तेल की बढ़ती हुई मांग पूरी करने में भी बहुत सहायता मिलेगी।

दो अवस्थाएँ

धानी से तेल-प्राप्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? दो अवस्थाओं में यह काम हो सकता है। प्रथम अवस्था है धानी में बिन कोई परिवर्तन किये तेल पेराई की प्रक्रिया में सुधार करना, उसे निर्दोष बनाना। इससे तुरन्त फल-प्राप्ति होगी। दूसरी अवस्था है स्वयम् धानी में कोई सुधार करना। इसके लिए अन्वेषण और क्षेत्रीय परीक्षण करना आवश्यक है। प्रस्तुत लेख में हम प्रथम अवस्था पर विचार करेंगे।

तेल पेराई का धना पुश्त-दर-पुश्त चलनेवाला एक परम्परागत पेशा बन गया है। कारीगर तेल पेराई की प्रक्रिया का ज्ञान हासिल करने अथवा अपनी धानियों में सुधार करने पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। यदि वे

इस पर वाञ्छित ध्यान देकर अपने पेशे के साथ न्याय करे तो न केवल वे निश्चित रूप से अपनी आमदनी ही बढ़ा सकते हैं, बल्कि इस उद्योग का वैज्ञानिक आधार पर विकास करने में सहायता भी दे सकते हैं।

तिलहन की रचना

पेड़-पौधे अपने बीजाकुरों के लिए आवश्यक खुराक तेल के रूप में अपने बीजों में संचित करते हैं। अकुरा-वस्था में इस तेल का, बीजाकुर उपयोग कर लेते हैं। पेड़-पौधे इस बात में पूरी सावधानी बरतते हैं कि उनके बीजों में जो तेल है उसकी बाह्य कारणों के प्रभाव से रक्षा हो। यह तेल बीज के सभी कोषाणुओं में बहुत अच्छी तरह माइक्रोस्कोप द्वारा ही देने जा सकते जैसे लवु कणों के रूप में फैला रहता है। प्रत्येक कण के चारों ओर श्वित्याभ कोष (एल्बुमिनीय सेल) पदार्थ होता है। उसके चारों ओर भी कोष-भित्ति (सेल वाल) होती है। इन सभी कोषों की सुसम्बद्ध यानी ठोस व्यवस्था से, तथा बीज के छिलके से, तेल-कणों को और भी अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। पेड़-पौधों ने तिलहन के लिए जो कुछ किया हो, उसे उट्टा कर देना तेल पेराई की प्रथम अवस्था है। पेराई में सुसम्बद्ध कोषों को खोलना होता है, उनकी भीतियाँ ढीली पड़ती हैं और तेल अन्दर से बाहर लाया जाना है। संक्षेप में यही तेल पेराई की प्रक्रिया है।

इस सबब में तीन तरीके प्रचलित हैं। वे तरीके हैं (अ) पायस (इमल्सन) तरीका, (आ) दबाव निष्सारण तरीका, और (इ) द्रावक निस्सारण तरीका। घानी, घर्षक, (रोटेरी), एक्मपेलर तथा द्रव चालित दाब में पेराई को दबाव निस्सारण तरीके के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि इसे दबाव निस्सारण तरीका कहा जाता है, तथापि अकेले दबाव से ही तेल नहीं निकल सकता। वस्तुतः दबाव का काम तो पूर्व के तीन कारकों के काम के बाद आता है। वे तीन कारक हैं घर्षण, गरमी और आर्द्रता। ये तीन कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना कि चौथा यानी दबाव, क्योंकि इन तीनों कारकों में से किसी में भी कोई दोष रहा तो उसका असर समूची प्रक्रिया पर पड़ता है और यहाँ तक कि वह दबाव को भी प्रभावहीन कर देता है। यद्यपि प्रत्येक कारक का अपना काम है, तथापि कोई भी अकेला कारक पूरी प्रक्रिया नहीं कर सकता। प्रत्येक एक-दूसरे के काम में मात्र सहायक ही होता है, तेल पेराई की प्रक्रिया सबके एक साथ मिलने पर ही पूर्ण होती है। यदि तिलहन प्रशोधन के काम में लगा कारीगर इन कारकों के महत्व के प्रति सजग हो तो वह सम्पूर्ण तेल निकालने में समर्थ होगा। इन सभी कारकों पर हम नीचे विस्तृत चर्चा करेंगे।

घर्षण

ऊँखल यानी घानी के गड्ढे में मूँसल और तिलहनो के एक-दूसरे के साथ रगड़े जाने से घर्षण पैदा होता है। मूँसल और भांग-पाट पर रखे वजन में पैदा हुए दबाव के साथ यह घर्षण तिलहनो को पीस देता है। चूँकि तिलहन का छिलका मुलायम ओर फिसलनेवाला होता, इसलिए बचन-कारी पदार्थ के रूप में काम करने तथा मूँसल को पकड़ प्रदान करने के लिए भी कुछ पानी छिड़का जाता है। घर्षण एकसम और साधारण होना चाहिए। इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि तिलहन लगातार डाले जाते हैं अन्यथा पिसाई समान नहीं होगी और तेल-प्राप्ति कम होगी। पेषण के वक्त भी तिलहनो का

लगातार डाला जाना आवश्यक है ताकि मूँसल और ऊँखल के पदे प्रत्यक्षत आपस में भिड़ें नहीं, क्योंकि परस्पर भिड़ने से उनमें खरोंच पड़ जाती है। तिलहन डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तिलहन घूमते हुए मूँसल से सटे रूप में पीछे न डाल कर उसमें कुछ दूरी पर आगे डाले जाते हैं। पीछे गिरनेवाले तिलहन मूँसल के आगे चलने से पीछे जो खाली स्थान बन जाता है, उसमें होकर ऊँखल के पेन्डे में जा सकते हैं, और फलस्वरूप मूँसल ऊपर खिसक सकता है। जल डालने में देर करने अथवा अपर्याप्त मात्रा में डालने से भी उक्त बात घट सकती है।

जल

साधारण तौर से भांगपाट पर २५० से ३५० पौण्ड तक वजन रखना पेषण के लिए पर्याप्त होगा। अलमी ओर खोपरे जैसे बहुत ही तन्तुमय तिलहनो के मामले में पेषण के वक्त अधिक वजन रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। साधारण स्थिति में पेषण के लिए, समूची प्रक्रिया में आवश्यक समय के एक-निहाई से अधिक वक्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। तिलहन में नमी अधिक होने, ज्यादा जल देने, भांगपाट पर अपर्याप्त वजन और बैलों की गति का बीमा होना कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से पेषण में कुछ ज्यादा समय लग सकता है।

धान में मही मात्रा में जल का डाला जाना सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इस सम्बन्ध में कुशलता की प्राप्ति दीर्घ-कालीन अनुभव के बाद ही हो सकती है। पानी की मात्रा तिलहन की किस्म और उनके मुखाये जाने की सीमा पर निर्भर करती है। आम तौर पर समूची प्रक्रिया में तिलहनो की मात्रा के करीब छ प्रति शत पानी की जरूरत पड़ती है। पानी चार बार भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में दिया जाता है। विभिन्न अवस्थाओं में उसमें अलग-अलग प्रयोजन मिश्र होते हैं। पेषण के वक्त यह बचन-सामग्री का काम देता है और तिलहनो को तथा तिलहनो व मूँसल के बीच अच्छी

पकड़ प्रदान करता है। इस वक्त दिया गया पानी कुछ देर बाद बतनेवाली खली को आवार भी प्रदान करता है। द्वितीय अवस्था में, गर्मी के साथ मिल कर यह कोष-परिकोटा को पकाता है और उसे कमजोर बनाता है। खली के बतने में इस वक्त का यह पानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

इस अवस्था के बाद कारीगर इस बात की जाँच करता है कि जल की मात्रा उपयुक्त परिमाण में दी गयी है अथवा नहीं। यह काम वह पिसान (यानी तिलहनो के घानी में पिसने के बाद बनी हुई चूर्ण जैसी सामग्री-मील) को हाथ में लेकर उसका गोला बना कर करता है। यदि पानी की मात्रा ठीक रही तो गोला अच्छी तरह बन्द जायेगा। और, कुछ दबाव डालने पर ही वह फूट सकता है। यदि पानी कम या अधिक रहा तो अँगुलियों से थोड़ा-सा दबाव डालने पर गोला बूर-चूर हो जायेगा। तीसरी बार पानी घानी के खड्डे से तेल निकालने के कुछ पहले दिया जाता है। इसका प्रयोजन तेल को साफ करना होता है, क्योंकि उसमें कुछ तलछट मिला होता है। पानी देने पर तलछट खली से चिपक जाता है और स्वच्छ तेल अलग हो जाता है। खली पर फेन जम जाने के बाद ही तेल अलग निकालना चाहिए। चौथी मर्तबा पानी खली को हटाने से एक-दो मिनट पहले दिया जाता है। इस बार केवल सिला हाथ फेर कर ही पानी दिया जाता है। यह पानी खली के ऊपर लगा हुआ अवशेष तेल अलग करने और खली को नरम तथा स्वच्छ बनाने के लिए दिया जाता है।

ताव देना

श्वित्याभ के गाढेपन और स्वच्छ तेल प्रवाह के लिए पिसान को उपयुक्त ताव देना आवश्यक है। सही रूप में पानी न देने की वजह से ताव देने में बाधा पड़ती है। पानी और गरमी की क्रिया से स्वयम् घानी के अन्दर ही ताव दिया जाता है। यदि ताव का दिया जाना अपूर्ण रहा तो अनेक कोष वैसे के वैसे रह जायेंगे तथा

उनमें तेल बच रहगा। इससे न केवल तेल-प्राप्ति पर ही असर पड़ेगा, बल्कि श्वित्याभ गाढा न होने से तेल गदला भी हो जायेगा। ये श्वित्याभ यदि गाढेपन के जरिये तेल पेराई के दौरान दूर नहीं किये जाते तो निस्थन्दन के द्वारा भी आसानी से नहीं हटाये जा सकते। इन श्वित्याभों में रही आद्रता मुक्त स्नेहाम्लों को स्वतंत्र कर देती है। सही-सही जल देना सही ताव की कुँजी है। तिलहनो में आद्रता, कभी-कभी पानी देने में गलती करवा देती है। इसलिए तिलहनो को घानी में डालने से पहले अच्छी तरह मुखा लेना सदैव ही अच्छा रहता है। अच्छी तरह सुखाये हुए तिलहनो का पेषण जट्दी और सरलतापूर्वक होता है।

पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से खली चिकनी और सख्त नहीं बन पाती। खली चिपचिपी और टुकड़ेदार होगी। इससे खली की दबाव सहने की शक्ति कम पड़ जाती है तथा फलस्वरूप उसका तेल-प्राप्ति पर बुरा असर पड़ता है। अपर्याप्त जल देने का भी तेल-प्राप्ति पर असर होता है, क्योंकि जल ही तेल कणों को उनके कोषों में अलग करता है। गरम अथवा उबलते हुए पानी को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि यह नितल के पिसान तक चला जाता है और अपनी स्वयम् की गरमी प्रदान करने के अलावा पिसान को घानी में प्रयुक्त गरमी हासिल करने में भी मदद देता है।

गरमी

घानी में पिसान को रगड़ते हुए, मूसल के घूमने से उत्पन्न घर्षण द्वारा गरमी पैदा होती है। कुछ कारीगर मसाल से पिसान को गरमी पहुँचाते हैं। कुछ अन्य कारीगर पेराई की प्रक्रिया के बीच ही तेल निकाल लेते हैं और उसे गरम करके पुनः घानी में डाल देते हैं। बेल की चाल धीमी होने के कारण पर्याप्त गरमी देते रहना सदैव ही एक समस्या रही है। जो कुछ थोड़ी-बहुत गरमी पैदा होती है वह भी किसी हद तक बिखर

जाती है। काष्ठ लथ्वा पत्थर—जो कि नाप-तुलाक हे—की धानियाँ बनाते के पीछे गरमी को सुरक्षित रखने की समस्या सम्भवतः बाध्य कर देनेवाला कारण रहा है।

कोष की परते पकाने और शित्प्राप्ति को गाढापन प्रदान करने ने भी गरमी जल के काम में मदद करती है। एक तरफ यह कोष की परत को पका कर कमजोर बनाती है तथा दूसरी ओर तेल कणों के विस्तार का कारण बनती है, जिसका परिणाम गिनतता है कोष का फटना और तेल का उससे बाहर जाना। अधिकतम गरमी पैदा करने और जो कुछ गरमी पैदा हो उसे बनाये रखने के लिए बैलों को जोर से हॉकना आवश्यक है। यह देखा जा सकता है कि एक घान की पेराई करने के लिए तेज चलनेवाले बैलों को अन्य बैलों की अपेक्षा कम बलकर लगाने पड़ते हैं।

दबाव

तेल को खली से अलग करने में दबाव बड़ी सी सीसादी किन्तु गिनयिक भूमिका अदा करता है। दबाव के कारण विभिन्न तेल कणों में समरसता स्थापित होती है। इन बून्दों यानी तेल कणों को एक साथ मिलने, एक बड़ा स्वरूप प्राप्त करने और खली से बाहर निकलने के लिए दबाया जाता है। यद्यपि पेषण और खली बनने जैसी प्रारम्भिक अवस्था में भी कुछ दबाव की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अन्तिम अवस्था में उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक अवस्थाओं में तिलहन को कई परिवर्तनों से हो कर गुजरना और अपने तेल तत्व के निस्सारण के लिए तैयार होना पड़ता है। तेल को तिलहन से वास्तव में अलग तो अन्तिम अवस्था में ही किया जाता है। यह अवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि कृषि-कार्य में फल कटाई की स्थिति होती है।

बैलों पर अधिक जोर न डालते हुए इस वक्त यथा सम्भव सर्वाधिक वजन खा जाना चाहिए, और जो कुछ भी वजन प्रदान किया जाय उसे घान की पेराई

पूरी होने तक रगाना चाहिए। यदि उस अवस्था के दौरान वजन में कमी हुई तो खली में तेल रह गकता है। यदि पेराई की प्रक्रिया के अन्त के समय हम धीरे-धीरे दबाव बढ़ा सकें तो, इसमें परिपूर्ण निस्सारण में सहायता मिलेगी। बीच में दबाव का कम पड़ जाना सर्वाधिक हानिप्रद है और इसलिए इसमें नचना चाहिए।

खली की मोटाई

खली जितनी ही मोटी होगी, उस पर दबाव का अमर उतना ही कम होगा। यद्यपि किमी हद तक खली की मोटाई स्वयम् दबाव पर निर्भर करती है, तथापि यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि प्रक्रिया की अन्तिम अवस्था में कारीगर उसे यानी खली को कितना सम्हालता है। खली को तोड़ने और घानी में डालने का काम एक रूढ़ि होना चाहिए। घानी में खली डालते वक्त स्थान के अन्तर की उपयुक्तता का भी खयाल रखना चाहिए। ज्यादा खली होने की वजह से उसकी मोटाई बढ़ जाती है, जिसका बैल और तेल-प्राप्ति दोनों पर बुरा अमर पड़ता है। एक अनुभवी तेलकार खली की मोटाई घानी के ऊपरी हिस्से पर करीब आध इंच और पेदे में तीन इंच रखेगा। मोटी खली में तेल तत्व अधिक रहता है और उसकी आर्द्रता बुखाने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए उसमें शीघ्र ही बदबू आने लगती है।

सामान्य दोष

खली बनने में देर होना अथवा उसका बिल्कुल न बनना एक सामान्य दोष है। यह दोष महुआ और मूंगफली जैसे अतन्तुमय तिलहनो में खाम तौर से अधिक होता है तथा खोपरा व कुमुम्भ जैसे बहुत ही तन्तुमय तिलहनो के मामले में प्रायः बिल्कुल नहीं पाया जाता। खराब तिलहन पेरने के कारण भी सामान्यतया यह समस्या खड़ी होती है। पेषण की उपान्त्य अवस्था में सावधानी बरत कर इस की नाई से बचा जा सकता है। खली का बनना तिलहन के पूर्ण रूप से पिस जाने से पूर्व

ही प्रारम्भ होना चाहिए। यदि दूसरी बार पानी देने में देर हो जाती है अथवा कम मात्रा में दिया जाता है तो तिलहन बहुत ही महीन पिस जाते हैं और फिर वे खली का रूप नहीं लेते। आवश्यक मात्रा में पानी देकर, भारपाट पर वजन कम करके और छड़ से पिसान को धीरे-धीरे हल्के हाथ से खोद कर यह दोष दूर किया जा सकता है। यदि पिसान गरम न हो तो उसमें मसाल से थोड़ा ताव दिया जा सकता है। फिर भी, यदि दोप दूर न हो तो तृण अथवा मृगफली के छिठके जैसी कुछ तन्तुमय सामग्री पिसान में मिलायी जा सकती है।

कारीगरों को कभी-कभी जिस दूसरे दोप का सामना करना पड़ता है वह है पेराई की प्रक्रिया के दौरान मूसल का ऊपर उठ जाना। ऐसा तब होता है जबकि घाँी के पेन्दे में बहुत अधिक पिसान इकट्ठा

हो जाय। मूसल कितना ऊपर उठता है, यह इस बात पर निर्भर है कि पेन्दे में कितना पिसान है। मूसल इतना ऊपर भी उठ सकता है कि वह अपनी पकड़ छोड़ दे और घाँी से बाहर गिर जाय। यदि यह दोप प्रारम्भिक अवस्था में हो तो पिसान को कम करके और बैलों की चाल बीनी करके उस पर काबू पाया जा सकता है। मूसल टेढ़ा और घूमनी हुई अवस्था में रहने के कारण पेन्दे का पिसान फिर ऊपर आ जाता है। दोप कुछ अधिक बढ़ जाने पर यानी उस वक्त जबकि मूसल एकाव इव ऊपर उठ जाय तब उसे उठा कर पेन्दे में से पिसान को हटाना पड़ेगा। मूसल को पुन ऊँचल में रख कर ओर शुरु में कुछ अच्छी तरह बनी हुई खली उसने डाल कर फिर से घान चालू किया जा सकता है।

मद्रास • ८ अक्टूबर १९६३

हमारे नवीनतम प्रकाशन ! प्रत्येक खादी कार्यकर्ता के लिए अपरिहार्य !!

बिक्री छूट के बदले बुनाई उपदान

(प्रस्तावना लेखक : वैकुण्ठ ल मेहता)

प्रस्तुत पुस्तिका में खादी और ग्रामोद्योग आन्दोलन से सम्बद्ध जाने-माने प्रमुख नेता नयी योजना (बिक्री छूट के बदले बुनाई उपदान) की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं।

बुनाई उपदान योजना का कार्यान्वय

बुनाई उपदान योजना को उसकी विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय, सदस्य-प्रमुख (खादी) इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। इस पुस्तिका में नयी योजना के अनुसार 'पड़ता तैयार करने का नमूना' भी दिया गया है।

मुफ्त बुनाई सेवा योजना

मुफ्त बुनाई योजना के विकास पर प्रकाश डालती है।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन

आमोदय, बम्बई ५६

गांधी सेवक समाज

वैकुण्ठ ल. मेहता

गांधी विचारधारा को माननेवाले कार्यकर्ता शहरी क्षेत्रों में समाज-कल्याण की दिशा में शहरीकरण की समस्याओं का अध्ययन करने पर ही प्रभावोत्पादक योगदान दे सकते हैं। गांधी स्मारक निधि की बम्बई शाखा ने नगरों तथा शहरों में आजीवन कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना बनायी है।

हर वर्ष ३० जनवरी को हम शहीद दिवस विशेष कर महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाते हैं, जोकि एक आततायी के शिकार हुए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन न्याय का सर ऊँचा रखने में उत्सर्ग किया तथा वे सबसे एक समान स्नेह करते थे। गत गांधी निर्वाण दिवस पर बम्बई में गांधीजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जैसा कि डा ई स्टेनली जोन्स ने कहा था कि हम लोगों में से बहुतों की कल्पना चन्द लोगो तक ही सीमित है, उसमें सभी लोग नहीं आ पाते जबकि गांधीजी की कल्पना में सब आ जाते थे। फिर, इन बहुतों में वैसे व्यक्ति और वर्ग हैं जिन्हें अपने समाज के बाहर के व्यक्तियों के लिए कोई स्नेह अथवा मोह है ही नहीं और यदि उनके प्रति अन्याय किया जाय तो वे उसकी परवाह नहीं करेंगे। जिस गुमराह व्यक्ति ने गांधीजी की हत्या की वह दूसरो को प्यार करने की बात तो दूर रही, उनसे घृणा करता था।

परन्तु ३० जनवरी शहीद दिवस होने के अतिरिक्त सर्वोदय पक्ष का प्रथम दिवस भी है। इस पक्ष में न हमसे सिर्फ इस बात का आग्रह किया जाता है कि हम गांधीजी के प्रिय कार्यों को आगे बढ़ाने में कितने सफल रहे हैं इसका मूल्यांकन करें, बल्कि इन कार्यों के विकासार्थ योजना बनाने के लिए भी कहा जाता है। उपर्युक्त दृष्टि से ही यह दिन गांधी स्मारक निधि के तत्वावधान में गांधी सेवक समाज नामक आजीवन कार्यकर्ताओं के एक नये सगठन के उद्घाटन के लिए चुना गया।

हम गांधीजी को पितामह अथवा राष्ट्रपिता मानते हैं। वे अपने को प्रथम भारत-सेवक अथवा भारत सेवकों में प्रथम कहलाना पसन्द करते। गोंपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधीजी अपना गुरु मानते थे, १९०५ में उन्हीं के द्वारा स्थापित हिन्दू सेवक समाज के प्रथम सदस्य थे। अफ्रीका में गांधीजी के भारत वापस लौटने पर उन्ही समाज का सदस्य बनने का आमन्त्रित किया गया, परन्तु दोनों के निर्णय करने के पूर्व ही गोखले १९ फरवरी १९१५ को चल बसे।

हिन्दू सेवक समाज

बाद में गांधीजी समाज के सदस्य तो नहीं बने, परन्तु उन्होंने उससे अपना सम्बन्ध बनाये रखा और उसके सदस्यों को अपना सहयोगी माना। माबरमनी आश्रम में बस जाने के बाद उन्होंने वैसे व्यक्तियों—युवकों और बूढ़ों—को अपने पास आकर्षित करना शुरू किया, जोकि अपने को देश सेवा में लगाने के लिए इच्छुक थे। जिस तरह हिन्दू सेवक समाज ने कई ऐसे व्यक्तियों को पेटा किया, जिन्होंने कि राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों में बहुत ही स्याति प्राप्त की, उसी तरह आश्रम में गांधीजी के निकट सम्पर्क में जो लोग आये उन्हें मुख्यतः राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों में ही प्रेरणा मिली। उनमें ऐसे ही व्यक्ति अधिक रहे जिन्होंने कि राजनीति से अधिक आदिवासियों, हरिजनों अथवा मजदूरों की सेवा में या फिर शैक्षणिक और समाज-कल्याण कार्यों में ही स्याति प्राप्त की।

हिन्दू सेवक समाज की नींव थी राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज-शास्त्र का गहन और क्रमबद्ध अध्ययन, अतः जो आजीवन कार्यकर्ता के रूप में उसके सदस्य बनना चाहते थे, उन्हें दो-तीन वर्ष तक प्रशिक्षणान्तर्गत सदस्य के रूप में रहना होता था। यह अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि आज हमारे समाज को निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जोकि समाज सेवा का कार्य पर्यवेक्षण काल में अध्ययन के तौर पर शुरू कर सके। गांधी स्मारक निधि के पास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की योजना है, लेकिन चूकि इसके अधिकांश कार्य गांवों की सेवा की ओर निर्दिष्ट है, अतः अब तक जिस किस्म का प्रशिक्षण दिया गया है, वह मुख्यतः ग्राम समाज के कल्याण कार्य के लिए ही उपयुक्त है।

शहरो में काम के लिए प्रशिक्षण

जैसा कि गांधीजी बार-बार कहा करते थे, 'भारत वाकई गांवों का देश है।' इसके साथ ही यह तथ्य भी स्वीकार करना होगा कि शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है और संचार का विकास होने के साथ-साथ गांववालों का शहरों से सम्पर्क भी बिल्कुल आदतन बन गया है। फिर, यद्यपि ग्राम समाज की समस्याएँ बहु-विध और जटिल हैं हाल के वर्षों में हमने जो अनियंत्रित तीव्र शहरीकरण होते देखा है, हमारे शहरों की समस्याएँ बढ़ गयी हैं और औद्योगीकरण ने कुछ ऐसी शक्तियाँ खड़ी कर दी हैं जिन पर निष्ठापूर्ण अध्ययन करने तथा ध्यान देने की जरूरत है। इन समस्याओं के सिलसिलेवार अध्ययन और हल के लिए ऐसे कई प्रशिक्षित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जैसे कि गोखलेजी के हिन्दू सेवक समाज से प्रेरणा प्राप्त करनेवाले कार्यकर्ता थे— अथवा गुजरात विद्यापीठ के महादेव देसाई स्नातकों की तरह जो ग्रामाभिमुखी हैं— जोकि मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में सेवा के लिए उपलब्ध होंगे।

गांधी स्मारक निधि का बम्बई मण्डल एक ऐसा अभिकरण है, जिसका कार्यक्षेत्र बृहत्तर बम्बई के शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है, अतः यह इस मंडल

पर ही निर्भर है कि वह कैसे आजीवन कार्यकर्ताओं की सस्था निर्मित करने की दिशा में अग्रणी हो जोकि पर्यवेक्षा-काल और क्रमबद्ध अध्ययन समाप्त कर पूर्ण मुसज्जित हो जन सेवा कार्य आरम्भ करेगे। पूर्ण प्रशिक्षणकाल में सदस्यगण एक ही स्थान पर रहेगे और उनके साथ ही शिक्षक रूप में समाज द्वारा चुना गया एक ऐसा योग्य व्यक्ति भी रहेगा जोकि उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और उनके अध्ययन में सहयोग देगा।

कल्याणकारी अभिकरणों का अध्ययन

यद्यपि 'अध्ययन' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम महज बड़े-बड़े ग्रन्थ और 'नील पुस्तको' के पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि काफी विस्तृत है। प्रशिक्षणान्तर्गत सदस्यों को बम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विभागों के अध्यक्षों के सम्पर्क में लाया गया है और उनके सम्पर्क में भी जोकि सर्वोदय विचारधारा के ज्ञाता हैं। यथा सम्भव शीघ्र ही बम्बई के विभिन्न समाज-सेवी अथवा समाज कल्याण अभिकरणों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि आजीवन कार्यकर्ता उनके कार्य-संचालन और सामाजिक जीवन में उनके स्थान का अध्ययन कर सकें। विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं के सर्वेक्षण की तैयारी करने में भी मार्गदर्शन दिया जायगा। इन अध्ययनों, विवरणों, सर्वेक्षणों पर—विभिन्न समस्याओं के सैद्धान्तिक पहलुओं के साथ—समाज के सदस्यों के साथ-साथ मुख्यतः शैक्षणिक क्षेत्रवाले उनके सलाहकारों के साथ चर्चा की जायगी। उसके बाद आजीवन कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध विशिष्ट समाज सेवा कार्य करनेवाली सस्थाओं से जोड़ा जायगा। बहरहाल उम्मीद की जाती है कि समाज की यह योजना वर्तमान सस्थाओं को अपनी कार्यशीलताएँ बढ़ाने में मदद देगी।

गांधी स्मारक निधि को अपनी इस अपरिमेय जिम्मेदारी का पूरा-पूरा भान है। कोई ऐसा भ्रम भी नहीं है कि कोई आधे दर्जन अथवा दर्जन भर आजीवन कार्यकर्ताओं

के बम्बई में इकट्ठा होने और प्रशिक्षण लेने से शहरीकरण की समस्याओं पर, जोकि दिनोदिन बढ़ती ओर उलझती ही जा रही हैं, तुरत कोई प्रभाव पड़ेगा। परन्तु सर्वोदय विचारधारा वाले कई व्यक्तियों का यह मत है कि इन समस्याओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने और इन्हें सिलसिलेवार ढंग से हल करने की जरूरत है। उनका हल करने के प्रयास करने के पूर्व तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर ज्ञानाधार प्राप्त करना तथा उन अवस्थाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करना जिनमें सर्वोदय के मूल सिद्धान्तों की समस्याओं का हल प्रयुक्त किया जा सके, अत्यावश्यक है।

सर्वोदय की व्याख्या है ऐसा समाज, जिसमें जोपण और वर्ग-भेद न हो, श्रम की प्रतिष्ठा हो और जो मनुष्य

के प्रति सम्मान बढ़ाये। इस सामाजिक परिवर्तन को लाने में परिणाम की शुद्धता पर भी उतना ही जोर है जितना कि माध्यम की शुद्धता पर और जोकि गांधीजी की शिक्षा के अनुसार मनुष्य और अहिंसक हो। हम लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत प्रगट कर अथवा सर्वोदय के लिए— अगर हम दोनों में विभेद करने हैं तो— नीचे से ही निर्माण करना होगा और गांधी ग्रामीण समाज के ठोस आधार हेतु सावधानीपूर्वक आयोजन और लठोरा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। गांधी स्मारक विधि का विश्वास है कि इस विशाल कार्य में गांधी सेवक समाज नामक इस नयी सम्पद्ध संस्था का निर्माण कर वह अपना वित्तिय योगदान दे सकेगी। [‘भारत उन्नति’, बम्बई से साभार।]

बम्बई, २१ जनवरी १९६४

विद्यार्थियों की वर्तमान पीढ़ी सन् २००० में भी काम-धंधों में लगी रहेगी, लेकिन उससे बहुत पहले ही उनकी डिग्रियाँ व डिप्लोमे अप्रचलित हो हो जायेंगे—विज्ञान, प्रविधि और सामाजिक विज्ञान सम्बन्धी डिग्रियाँ तो निश्चय ही समय अथवा परिवर्तन की दौड़ में पीछे रह जायेंगी। इस अप्रचलितता से केवल चन्द वे ही छात्र निश्चित रूप से बच सकेंगे, जो स्वयम् आविष्कारक बन जायेंगे। शेष छात्रों—जोकि हमारे मानवीय साधन-स्रोतों का महान बहुमत है—में हमारा जो विनियोजन है, प्राविधिक तथा सामाजिक परिवर्तनों के कारण उसका निश्चय ही अवमूल्यन हो जायेगा। इसलिए इस अप्रचलितता से लोहा लेने अर्थात् उनके प्रमाण-पत्रों आदि को समय अथवा विविध परिवर्तनों के समक्ष पीछे न पड़ने देने सम्बन्धी उपायों का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है।

—सर एरिक अँशबी ‘इनवेस्टमेण्ट इन
मैन,’ न्यू साइन्टिस्ट, लन्दन।

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए ‘ग्रामोदय,’ इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ से प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल एमोसिप्टेड एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ५०५, तारदेव, आर्थर रोड, बम्बई-३४। वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ नये पैसे।

दशम वर्ष • अप्रैल १९६४ • सप्तम अंक



	पृष्ठ
खादी आन्दोलन का नया अध्याय	४५९
परिगणित जातियो तथा जन-जातियो के लिए रोजगारी	
खादी कार्यक्रम और उसकी आलोचना	—उत्तरंगराय न. टेबर ४६३
ग्रामोद्योगो के लिए मध्यम प्रौद्योगिकी	—वैकुण्ठ ल. मेहता ४६७
लघु उद्योगो के लिए प्रौद्योगिकी	—त्रिभुवन नारायण सिंह ४७३
ग्रामीण औद्योगीकरण	—दया कृष्ण मल्होत्रा ४७८
दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा	—पुतुपरम्बिल म. मथाई ४८१
खादी उद्योग मे वैज्ञानिक दृष्टि	—लालभाई र. देशाई ४८५
उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन और ग्राम इकाई	—शंकरलाल बैकर ४९०
ग्रामीण क्षेत्रो मे गैस सयत्र	—प्रमोद कुमार पटनायक ४९४
औद्योगिक सहकारी समितियाँ	—दत्तात्रेय ना. वान्देकर ४९९
समग्र विकास कार्यक्रम	—मसूद अली मिर्जा ५०२
आध्र प्रदेश की दस्तकारियाँ	—कोदण्डरामन वैद्यनाथन ५०५
त्रिपुरा की अर्थ-व्यवस्था और	—श्रीपति रंगनाथ ५०७
खादी-ग्रामोद्योगो की सम्भावना	५१०
पुस्तक समीक्षा	५१३

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोदय', इला, बम्बई-५६ से मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थ शास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकासके ध्येयसे लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ के पते पर भेजे। टेलीफोन नं. ५७१२२९।

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ नये पैसे। चन्द की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिये अस्सिस्टेण्ट एकाउण्ट्स ऑफिसर (कैश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६।

इस अंक के लेखक

उल्लरगाराय नवलशकर डेबर

वेंकण्ठ लल्लूभाई मेहता

त्रिभुवन नारायण सिंह

दया कृष्ण सहोत्रा

पुतुपरम्बल मथाई मथाई

लालभाई रतनजी देसाई

शकरलाल घेलाभाई बंकर

प्रमोद कुमार पटनायक

दत्तात्रेय नाथोबा घान्देकर

मसूद अली मिर्जा

कोदण्डरामन वेंद्यनाथन

श्रीपति रंगनाथ

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष।

—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य।

—योजना आयोग के सदस्य (उद्योग)।

—योजना आयोग के संयुक्त सचिव।

—भारत सरकार के सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उद्योग निर्देशक।

—अहमदाबाद स्थित गुजरात विश्वविद्यालय के उप-कुलपति।

—प्रख्यात अनुभवी रचनात्मक कार्यकर्ता।

—उड़ीसा सरकार के भुवनेश्वर स्थित उप-परीक्षक।

—बम्बई राज्य के भूतपूर्व उप-मंत्री और प्रसिद्ध अनुभवी समाज सेवी।

—अलीगढ़ स्थित मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में लेक्चरर।

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में समग्र विकास कार्यक्रम के निर्देशक।

—मद्रास स्थित जनसंख्या का अध्ययन करनेवाली संस्था 'इंडियन इस्टीमेट ऑफ पापुलेशन स्टडीज' के हैदराबाद स्थित वरिष्ठ गवर्णना अधिकारी।



खादी आन्दोलन का नया अध्याय

दूसमहीने की ६ तारीख से बुनाई उपदान (सब्सिडी) की नयी योजना लागू होने के साथ खादी आन्दोलन, विकास की एक नयी अवस्था में कदम रखेगा। खादी कार्यक्रम की शुरुआत, ग्रामीणों को अपने रहन-सहन की हालतें सुधारने में मदद देने के लिए की गयी थी। जितने लोगो ने इस कार्यक्रम को अपनाया है, उनकी सख्या से यह आका जा सकता है कि निश्चय ही यह मददगार रहा है। सन् १९५३ में अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के गठन के बाद एक दशक की अवधि में खादी के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वह १९५३-५४ में ९७ लाख १३ हजार वर्ग मीटर था जो वर्ष १९६२-६३ में बढ़ कर ७ करोड़ ४६ लाख ५१ हजार वर्ग मीटर तक पहुँच गया। इसी प्रकार बिक्री भी बढ़ी है। वर्ष १९५३-५४ में वह १ करोड़ २९ लाख ९८ हजार रुपये की हुई थी और १९६२-६३ में २० करोड़ ३७ लाख रुपये की। खादी कार्य में रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों की सख्या १९५३-५४ में ३ लाख ७९ हजार थी, वह १९६२-६३ में बढ़ कर १७ लाख ९९ हजार तक जा पहुँची। सामान्य दृष्टि से देखने पर कार्यक्रम को सफल कहा जायेगा। तथापि, आमतौर पर खादी बिक्री के लिए बनायी जानेवाली वस्तु ही रही है। बाजार अर्थ-व्यवस्था की अवस्थाओं के अन्तर्गत यह कोई अमाधारण बात भी नहीं है, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन सामान्यतः विनिमय के लिए होता है।

बहरहाल खादी चन्द नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इसलिए खादी कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता का उपयुक्त मूल्यांकन उत्पादन, बिक्री और रोजगारी के 'आर्थिक सूचकांकों' के सन्दर्भ में नहीं किया जा सकता। गांधीजी के अनुसार "खादी का चिरस्थायी महत्व तभी हो सकता है जबकि उसे अहिंसक ग्रामोत्थान अथवा ग्राम पुर्ननिर्माण के व्यापक कार्यक्रम के अंग रूप चलाया जाय।" इस दृष्टि से कार्यक्रम उसी हद तक सार्थक होगा, जिस हद तक वह ग्रामीण जीवन पर कोई प्रभाव पैदा करने में सफल होता है। देश के ग्रामवासियों की गरीबी को जानते हुए गांधीजी ने महसूस किया कि ग्रामीणों को उत्पादन करने के लिए तैयार करना ही पर्याप्त नहीं हो सकता जोकि अपेक्षाकृत आसान है, बल्कि उन्हें अपने उत्पादन का इस्तेमाल करने में समर्थ बनाने के लिए साधन और तौर-तरीके ढूँढ निकालना आवश्यक है, जोकि इतना आसान नहीं है। यही सूतकारों से आदतन खहरधारी बनने का आग्रह करने का महत्व निहित है। तथापि, बाजार अर्थ-व्यवस्था के अमर्यादित प्रभाव के कारण खादी और ग्रामोद्योगों का काम करनेवाले कारीगरों को कोई बहुत बड़ी सख्या में अपने खुद के उत्पादनों का उपयोग करने के लिए तैयार करना सम्भव नहीं बन पडा है।

गाँवों में अधिकांश लोगो को घोर गरीबी में रहना पडता है। इस कारण वे अपने खुद के परिश्रम से प्राप्त

फलों का आनन्द उठाने से ही वंचित हो जाते हैं। यह सभी जानते हैं कि गाँवों में शहरी की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय कम है। फिर, स्वयम् गाँवों में भी आमदनी और सम्पत्ति के सम्बन्ध में महान् अमानताएँ पायी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी संख्या को भुखमरी की हालत में रहना पड़ता है। बताया जाता है कि महालनोबीस समिति ने कहा है कि “यह निःकर्म न्यायोचित लगता है कि दस वर्ष के आयोजन के बाद भी और उच्च आय पर भारी कराधान की योजना के बावजूद शहरी आय में काफी संकेन्द्रण है। ग्रामीण आमदनी के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। उनके मामले में उच्च आयवालों पर भी कराधान का अधिक भार नहीं है।”

केन्द्रीय योजना मंत्री ने २६ अगस्त १९६३ को एक वक्तव्य दिया था, उसके अनुसार सबसे गरीब नितल श्रेणी के दस प्रति शत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में आठ और शहरी क्षेत्रों में दस रुपये मासिक खर्च करते हैं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च २७ नये पैसे से कुछ अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में ३३ नये पैसे हैं। उसी वक्तव्य के अनुसार देहाती इलाकों में ७० फी सदी लोग रोजाना पचास नये पैसे से कम ही खर्च कर सकते हैं। (और, देश की अस्सी प्रति शत से अधिक जनता गाँवों में रहती है।) दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि २५ करोड़ १९ लाख व्यक्ति प्रति दिन प्रति व्यक्ति पचास नये पैसे भी खर्च नहीं कर सकते। इतनी कम आय निश्चय ही लोगों की खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-से लोग कपड़ा और अन्य ग्रामोद्योगी माल खरीदने की हालत में नहीं हैं।

इस तरह की परिस्थिति में किसी ऐसी योजना के लिए विचार करना पड़ा, जिससे ग्रामोद्योगी उत्पादक अपने उत्पादन के लाभ में हिस्सा बढ़ाने में समर्थ हो सकें। इसलिए एक निर्णय किया गया है कि गाँवों में हाथ कते सूत की बुनाई पर उपदान दिया जाय। इस योजना के अनेक लाभ हैं, उदाहरणार्थ

प्रथम, यह उन ग्रामीण सूतकारों को, जो कि कपास भी उगाते हैं, वस्तुन दिन की कमी मूल्य के कपड़े की पूर्ति सुनिश्चित करेगी। गांव के बहुत-से लोगों के लिए, जो कि पमें की कमी के कारण कपड़ा खरीदना बहुत ही कठिन पाने हैं किन्तु जिनके पास काम करने के लिए समय है तथा जो काम करने के उच्छुक हैं, यह योजना निश्चय ही एक वरदान सिद्ध होगी।

द्वितीय, गाँवों के उन सूतकारों को जो कि कपास नहीं उगाते हैं, यह बहुत ही मामूली कीमत पर—कोई तैतीस नये पैसे प्रति बर्ग गज—कपड़े की पूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसका महत्व तभी समझा जा सकता है, जबकि इस पर ग्रामीणों की जीवन स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय निस्सन्देह अधिकाधिक ग्रामीण कताई की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि इससे वे सिर्फ अपने परिश्रम की कीमत पर अपना वस्त्र प्राप्त कर लेंगे।

तृतीय, जो ग्रामीण सूत नहीं कातते, उन्हें बहुत कम कीमत पर वस्त्र प्राप्त होगा, जो कि अभी के मुकाबले मिल वस्त्र की तुलना में काफी सस्ता होगा। चूँकि काता गया अधिकांश सूत गाँव में ही बुन लिया जायेगा, और जिसके कि गाँव में ही उपयोग कर लिये जाने की उम्मीद है, इसलिए परिवहन खर्च की वचत हो जायेगी। इस प्रकार इस नयी योजना के अन्तर्गत गाँवों में खादी बाजार के विस्तार की वास्तविक सम्भावना है और धीरे-धीरे खादी की खपत के लिए शहरी बाजारों पर निर्भरता भी बहुत कम की जा सकती है।

चतुर्थ, शहरी ग्राहकों को उसी कीमत पर खादी मिलेगी, जिस पर अभी मिलती है, इसलिए अभी जो लोग खादी खरीदते हैं, वे खादी नहीं खरीदेंगे, इसके लिए कोई आधार नहीं है।

बुनाई उपदान योजना लागू करने का निर्णय खादी कार्यक्रम का ग्रामीणों के जीवन से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जानबूझ कर लिया गया है। ग्राम इकाई की दिशा में भी यह एक तर्क संगत कदम है, क्योंकि उसकी कल्पना भी देहाती क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की

खेतिहर और गैर-खेतिहर कार्यशीलताओं के संयोजन पर की गयी है। इस प्रकार इसके पीछे यह बात सामने लाने का विचार है कि कृषि तथा खादी-ग्रामोद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ तक खादी और अनेक ग्रामोद्योगों के कार्यक्रम से लोगों को पूरक आमदनी का जरिया प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, अकेले इन उद्योगों के जरिये ही गाँवों की अर्थ-व्यवस्था में—जोकि सदा की भाँति कृषि-प्रधान है—कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्ष १९६३-६४ के लिए किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि साधारणतया इस बात को मान्यता दी जाती है कि अन्य क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए एक विस्तारशील कृषिक अर्थ-व्यवस्था का होना परमावश्यक है। कृषि क्षेत्र द्वारा उपयुक्त योगदान दिये बिना राष्ट्रीय आय, बचत अथवा निर्यात के क्षेत्र में वांछित वृद्धि करना मुश्किल होगा। और, न ही लागत तथा कीमतों को इस कदर कम रखा जा सकता है कि विकास की प्रक्रिया निर्बाध गति से आगे बढ़ रही रहे।* तथापि, कृषि क्षेत्र की प्रगति बहुत ही असन्तोष प्रद रही है।

कृषि उत्पादन जोकि १९६१-६२ में १९६०-६१ के रेकार्ड स्तर से १२ प्रति शत बढ़ा था, प्रतिकूल मौसम के कारण १९६२-६३ में ३३ प्रति शत गिरा। चावल और गेहूँ के उत्पादन में काफी गिरावट आयी, यद्यपि अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। कपास के अलावा अन्य सभी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में गिरावट आयी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गाँवों में हो रहे परिवर्तन कोई खास नहीं है।

देहात में निष्क्रिय जन-शक्ति का बाहुल्य है। उसके उपयोग से न केवल देहात के इलाकों में रोजगारी के मामले में बल्कि पूँजी-निर्माण के सम्बन्ध में भी योग मिल सकता है। यह सच है कि ग्रामोद्योगों से केवल मामूली बचत ही हो सकती है, तथापि वह यथार्थ है। पूँजीवादी ढंग के

उत्पादन से जो वचन अथवा अतिरिक्त बढ़ती होती है, उसमें व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी करने का ध्यान नहीं रखा जाता। सामाजिक मूल्यों से यह बिल्कुल परे है अर्थात् सामाजिक आचार-विचार के लिए इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं। जैसे कृषिक क्रान्ति को एक ऐसी प्रक्रिया बताया गया है जिससे मानव जैविक परिवर्तकों (पेड़-पौधे और पशु) का नियंत्रक तथा वृद्धि कर्ता बना, वैसे ही औद्योगिक क्रान्ति को वह प्रक्रिया बताया गया है जिससे जड़ पर्वतों के माध्यम से ऊर्जा के नव स्रोतों का दीर्घ स्तरीय उपयोग होने लगा। भारत औद्योगिक क्रान्ति की देहरी पर खड़ा है। जैसा कि प्रोफेसर रोस्टोव (Rostow) कहते हैं, आर्थिक विकास अपने आप नहीं हो जाता। यदि किसी समाज को “उच्च औसत विकास दर कायम रखनी है तो उसे परिमन्दन से अवश्य ही निरन्तर लोहा लेते रहना चाहिये, क्योंकि जहाँ आधुनिक विज्ञान और प्रविधि रिकार्डों के सिद्धान्त ‘ह्रासमान प्रतिफल’ को अनिश्चित काल के लिए दूर करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, वहाँ जो समाज इस क्षमता का फायदा उठाना चाहता है, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह पुराने अग्रणी विभागों के परिमन्द पड़ने पर उनमें वास्तव में नव उत्पादन-कार्यों का समावेश करने का फिर से कष्ट उठाये, और उसे इसके प्रत्यागित विस्तारशील प्रभावों का साहसपूर्वक फायदा उठाने की क्षमता का अवश्य ही प्रदर्शन करना चाहिए।” अनवरत आगे बढ़ने की स्थिति के लिए नयी और शक्तिशाली प्रवन्धवाली नयी तकनालाजी के संगठन की, नये ढंग के कर्मियों की, नये ढंग की वित्तीय तथा बिक्री व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के लिए न केवल नयी प्रविधि का समावेश करना आवश्यक है,

§ डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव का लेख ‘लीडिंग सेक्टर में एड डि टेक-ऑफ’ उनके ही द्वारा सम्पादित, इकनॉमिक ऑफ टेक-ऑफ इण्डू स्ट्रस्टेज ग्रोथ में, लन्दन, १९६३, पृष्ठ ९।

* भारत सरकार इकनॉमिक सर्वे, १९६३-६४, फरवरी १९६४, नयी दिल्ली, पृष्ठ ७।

वर्क एक शक्तिशाली प्रबन्ध, नये प्रकार के कार्यकर्ता, नये ढंग की वित्तीय तथा बिक्री व्यवस्था का खड़ा करना भी उतना ही आवश्यक है। यह एक राष्ट्रव्यापी काम है तथा खादी और ग्रामोद्योग जैसे किसी भी एक संगठन के, जिसका कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित है, बूते के बाहर की चीज है।

कमीशन अन्य क्षेत्रों में—खास कर कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में—हुई प्रगति का सफलतापूर्वक लाभ उठाने के बाद ही प्रभावशाली योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शक्तिशाली प्रबन्ध की स्थापना शिक्षा के विस्तार पर निर्भर करती है। ग्रामोद्योगों के काम में लगे कारीगरों की घोर गरीबी के कारण वित्तीय तथा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था भी उस प्रकार की व्यवस्था से भिन्न करनी होगी, जो कि उपयुक्त पूँजी-आधारवाले उद्योगों को काम दे सकती है। इस क्षेत्र में लगी अधिकांश संस्थाएँ और सहकारी समितियाँ अपने व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूँजी जुटाने में समर्थ नहीं हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें कमीशन द्वारा प्रदत्त वित्त पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस हद तक वित्त की उपलब्धि ने खादी तथा ग्रामोद्योगों में लगी संस्थाओं की संख्या को—और कुल उत्पादन, बिक्री व रोजगारी के परिमाण को भी—बढ़ाने में प्रेरणा दी है उस हद तक वह, कार्यक्रम और कमीशन द्वारा किये गये अब तक के प्रयासों की उपयोगिता का प्रमाण है। यह सच है कि संस्थाएँ तुरन्त अपना बकाया ऋण चुकाने अथवा उसके बिना काम चलाने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन ऋण-पूँजी का प्रयोग करना किसी भी हालत में खादी व ग्रामोद्योगों का काम करनेवाली संस्थाओं की ही विशेषता नहीं है। यहाँ तक कि बहुत ही बड़ी-बड़ी जॉइन्ट स्टॉक कंपनियाँ भी अपनी पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए ऋण-पत्र जारी करके ऋण-पूँजी जुटाती हैं। कुछ तो इस कारण कि देहातों में पूँजी की अपेक्षाकृत कमी है और कुछ इस वजह से कि

ग्रामोद्योगी उकाउरों का पूँजी आधार कमजोर है, वे खुले बाजार में पर्याप्त निधि जुटाने में असमर्थ हैं। वे केवल सरकार में ही आधा कर सकती हैं।

बिना काम रहनेवाले ग्रामीण जन समूह को रोजगारी प्रदान करने और ग्राम्य क्षेत्रों में गैर-व्यतिहर उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से ग्रामोद्योगों के विकास को सहायता देने की सरकारी नीति का सभी वर्गों के लोगों ने समर्थन किया है। और, यही वह नीति है, जिसके अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योगों का कार्यक्रम बनाया गया। इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता तथा प्राविधिक मार्गदर्शन देने के लिए कमीशन की स्थापना हुई। इस क्षेत्र में हमने काफी सफलता भी प्राप्त की है। तथापि, यदि संस्थाओं से ऋण—जो कि उन्होंने मचालन पूँजी अथवा स्टॉक, कच्चा माल आदि प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कर रखा है—वापिस करने के लिए कहा जाता है तो जो सफलताएँ मिली हैं, उनके निष्फल हो जाने का डर है, क्योंकि इससे अधिकांश संस्थाओं को अपना कारोबार बन्द करना पड़ेगा।

इन संस्थाओं को अधिक बचत करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उत्पादन के लिए बेहतरीन तकनीकों और उपकरणों की खोज करने के दृष्टिकोण से अनुसंधान व प्रविधि के विकास पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। नयी प्रविधि के लिए अधिक निवेश और उच्च स्तरीय शिक्षा की आवश्यकता होती है, और ये दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में सहज ही प्राप्य नहीं हैं। वस्त्रोद्योग विशेषज्ञों की एक समिति ने यह पाया है कि छ तकुएवाले सयुक्त अम्बर चरखे के नवीनतम नमूने पर छ घण्टे काम करके एक सूतकार एक रुपये की प्राप्ति कर सकता है। क्षेत्र में इन नये चरखे के प्रचलित हो जाने पर सूतकारों की उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने की दिशा में निश्चय ही बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। ●

परिगणित जातियों तथा जन-जातियों के लिए रोजगारी*

• उछरंगराय न. डेवर

परिगणित जातियाँ तथा परिगणित जन जातियाँ अपनी हालत में सुधार कर सकें, इसके लिए विशेष प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे और रोजगारी, प्रशिक्षण व उबार प्राप्ति के सम्बन्ध में उन्हें सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

परिगणित जातियों व परिगणित जन-जातियों के लिए

रोजगारी के विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन करने के लिए योजना आयोग बधाई का पात्र है। यह पहली मर्तबा है कि सरकार तथा योजना आयोग बेरोजगारी की समस्या पर एक समस्या के रूप में गौर कर रहे हैं। अब तक रोजगारी के मवाल पर सामान्य आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से ही विचार किया जाता रहा है।

परिगणित जातियाँ तथा परिगणित जन-जातियाँ, ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनकी एक विशेष स्थिति है। परिगणित जातियों को धर्म के नाम पर तथा परिगणित जन-जातियों को प्रादेशिक तथा अन्य प्रकार के अवरोधों—स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा पृथक्कृत्य थोपने की जानबूझ कर अख्तियार की गयी योजना के फलस्वरूप उत्पन्न अवरोध—के जरिये जानबूझ कर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रधान प्रवाह से अलग रखा गया है। इसलिए इन लोगों से सम्बन्धित बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की कोई साधारण समस्या नहीं है। इसका अपना विशेष स्वरूप है, जिसके लिए अलग टग से बड़े सोच-समझ के कदम उठाने की आवश्यकता है।

नया उपागम

रोजगारी असल में उत्पादन से पैदा होती है। लेकिन जब एक सामाजिक वर्ग जान-बूझ कर देश की अर्थ-व्यवस्था से अलग कर दिया जाता है, तब वैसी अवस्था

में उत्पादन के लाभ उम वर्ग तक कभी नहीं पहुँच सकते। इस सम्बन्ध में 'दि अदर अमेरिका' नामक पुस्तक का उदाहरण दिया जा सकता है। इस पुस्तक में इस सम्बन्ध में तथ्य और आकड़े दिये गये हैं कि अमेरिका में काले लोगों की सामान्य आर्थिक प्रगति को दवाने के लिए किम प्रकार उन्हें जान-बूझ कर बचित रखा गया है, अन्यथा प्रत्येक अमेरिकी समृद्ध बन सकता था। इसलिए योजना बनाने अथवा उसके कार्यान्वयन से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को सदैव ही यह विभेद ध्यान में रखना होगा। योजना आयोग ने इस ओर ध्यान दिया है, यह मेरी दृष्टि से इन व्यक्तियों के जीवन में एक नये युग का प्रारम्भ दर्शाता है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद

परिगणित जातियों तथा जन-जातियों के लिए रोजगारी के जो जरिये सामने आये हैं उन पर काफी चर्चा हुई है। योजना आयोग तथा भारत सरकार का ध्यान एक दूसरी ओर खींचा जा सकता है। वास्तव में इनके लिए नये अवसरों का सृजन करना चाहिये, लेकिन अगर हम आजादी हासिल करने के बाद सरकार ने जो काम-खास करके परिगणित जन-जातियों के सम्बन्ध में—किया है, उसका अध्ययन करे तो देखेंगे कि जो अधिकार तथा अवसर पहले से मौजूद थे, उन्हें सुरक्षित रखने तक में भी सरकार बुरी तरह असफल रही है।

* नयी दिल्ली में योजना आयोग द्वारा आयोजित दिनांक २० जनवरी से १ फरवरी १९६४ तक सम्पन्न 'परिगणित जातियों व परिगणित जन-जातियों को रोजगारी' विषयक विचार गोष्ठी

में दिये गये माषण पर आधारित।

† माइकल हैरिंगटन 'दि अदर अमेरिका' (स रा अमेरिका में गरीबी), पेब्लिन, पृष्ठ १८६।

मैं इस तथ्य में शायद कभी भी जानकारी नहीं कर पाता, लेकिन स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त के मौज्य से मुझे अनुसूचित क्षेत्रों और परिगणित जन-जाति आयोग के सम्बन्ध में काम करते वक्त यह सब जानने का मौका मिला। परिगणित जन-जातियाँ जिन जमीन पर तथा जिस जगल में वे रहती थी उनकी व्यवहागत पूर्ण रूपेण मालिक थी। अपनी जमीन और जगलों के प्रति उनका कितना लगाव है, इसमें बहुत कम लोगों की जानकारी है। मन् १७८९ और १९४१ के बीच १४ विद्रोह हुए हैं- सबके सब भूमि तथा जगलों के सम्बन्ध में उनके अधिकारों को लेकर। उनका प्रथम अधिकारापहरण १७८९ में हुआ। उसको लेकर १७८९, १८०० १८०७ और १८०८ में छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह हुए। तब के बाद कुछ समय शांति रही। सन् १८३० में फिर गडबड हुई और प्रसिद्ध कोल विद्रोह हुआ। विद्रोहों का तीसरा चरण १८५५ में सन्थाल विद्रोह के साथ शुरू हुआ। उसके बाद १८६२ और १८७९ में कोया विद्रोह तथा १८८७ में सरदारी सघर्ष हुआ। अन्त में १८९५ के बिरसा आन्दोलन से बाध्य हो कर अंग्रेज सरकार को १९०८ में अपनी भूमि नीति में सशोधन कर कानून बनाना पड़ा, जिसके अन्तर्गत व्यवस्था की गयी कि सरकार की पूर्वानुमति लिये बिना किसी भी आदिवासी भूमि का हस्तांतरण न किया जाय। इस पर भी १९११ में बस्तर विद्रोह, १९२५ में कोया विद्रोह और १९४१ में गोण्ड विद्रोह हुए। भूमि पर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन आदिवासियों को अपना खून बहा कर जो कीमत चुकानी पड़ी, वह एक ऐसी बात है जिसमें अन्य भारतीय बिल्कुल अनभिज्ञ हैं।

संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना

इस अनुभव और प्रायः श्री ठक्कर बाप्पा के एकमेव प्रयासों के फलस्वरूप परिगणित जन-जातियों को उनकी जमीन पर उनके अधिकारों का आश्वासन देने का भारत के संविधान में जान-बूझ कर प्रावधान रखा गया। इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुसूची ५ में

विशेष व्यवस्था की गयी है और सरकार को विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। फिर भी, यह एक दुःखद घटना है—और उसमें भी बरी बात तो यह है कि वह गांधीजी के देश में घट सकती है—कि विशेष प्रावधान के होते हुए भी उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम गाँव ही उठाया गया हो। बहुत कुछ भूमि आदिवासियों के हाथ में निकल गयी है। ठेकेदारों, साहूकारों आदि की शोषणकारी प्रवृत्तियों के कारण हुए हस्तांतरण के अलावा सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के फलस्वरूप भी आदिवासियों को अपने काफी क्षेत्र से वंचित होना पड़ता है। भूमि सृधारों में अधिकार स्थानों में उनका हित होने की अपेक्षा अहित ही अधिक हुआ है। धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, भवन निर्माण तथा अन्य विभागीय कामों के लिए—सिंचाई सम्बन्धी कार्यों की तो बात ही छोड़िये—सरकार ने संवैधानिक कर्तव्यों का बिना कोई खयाल किये भूमि प्राप्त की है। आये दिन तथा कथित स्वेच्छित समर्पण स्वीकार किये गये हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरों ने भी—जन-जातियों के हितों की रक्षा करना जिनका कर्तव्य है—उनकी जमीन खरीदी है।

नयी व पुरानी नीतियाँ

जगलों के सम्बन्ध में भी यही घटित हुआ है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद १९५२ में भारत सरकार ने १८९४ में बनायी गयी पुरानी अंग्रेज नीति में सशोधन किया। उक्त दोनों कानूनों के अन्तर से स्पष्ट पता चलता है कि नये कानून में एक रोजमर्रा के काम की तरह किस प्रकार आदिवासियों के हितों को ताक पर उठा कर रख दिया गया—केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय इसकी ओर से आँख मूद कर बैठा रहा। पुरानी नीति में कुछ शर्तों के साथ वन्य भूमि कृषि के लिए देने की व्यवस्था थी। नयी नीति में ये रियायतें वापिस ले ली गयी। पुरानी नीति में आरक्षित जगलों के बाहरी क्षेत्रों का कुछ हिस्सा पास-पड़ोस के गाँवों की आवश्यकता पूर्ति के लिए छोड़ा गया था। नयी नीति अर्थात् कानून में तय किया गया

कि इस काम के लिए गाँव के अलग में जगल होने चाहिये। पुरानी नीति में आदिवासियों के निजी जगलो में दखल न देने की बात थी। नयी नीति में उन पर भी समान नियंत्रण लागू होता है। पुरानी नीति जगलो में पशुओं को मुफ्त में चरान पर लागू नहीं होती थी। नयी नीति में पशुओं को चराने की बात को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गयी है। और, यह सब नियंत्रण पशु-चराई न्यूनतम करने के लिए सोचे-समझे उद्देश्य में लागू किया गया।

अनुसूचित क्षेत्रों और परिगणित जन-जाति आयोग ने जमीन तथा जगलो पर आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए त्रास्तिकारी सिफारिशें की हैं। सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन हैं। आशा की जा सकती है कि पिछले सोलह वर्षों में जो कुछ हुआ है, उसके विपरीत इन सिफारिशों के अनुसार ठोस कदम उठाये जायेंगे। जब तक आदिवासियों को हमने जो आश्वासन दिये हैं, उन पर अमल न किया जाय और जो कुछ उनका है वह उन्हें न प्रदान किया जाय, तब तक कोई भी आदिवासी भविष्य के सम्बन्ध में हमारे आश्वासनों पर विश्वास करनेवाला नहीं है। संविधान में विशेष व्यवस्था की गयी है और उसका लाभ न उठाने के लिए कोई कारण अथवा औचित्य नहीं है।

सेवाओं में प्रवेश

इन दो वर्गों के सेवाओं में प्रवेश करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रदत्त आँकड़ों से पता चलता है कि १९५७ में १४,००० आवेदन-पत्र आये जिनमें से २,००० उम्मीदवारों के नामों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गयी, जबकि १९५९ में प्रार्थना पत्रों की संख्या बढ़कर २४,००० हुई और परीक्षा के लिए करीब १६,००० व्यक्ति उपस्थित हुए तो भी केवल १,१०० व्यक्तियों के नामों की ही नियुक्ति के लिए सिफारिश की गयी। यदि कोई परिगणित जातियों तथा जन-जातियों से सम्बन्धित संस्थाओं में स्थिति का अध्ययन करे जहाँ अधिकांश व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है, तो पता

चलेगा कि कहानी कोई भिन्न नहीं है। यही बात खेती, वाणिज्य तथा व्यवसाय और औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। कारीगरों के क्षेत्र में भी उनका स्थान नगण्य है। अभी तक हम 'लोकतन्त्रात्मक समाजवाद' की भावना समझ ही रहे हैं। हम उन व्यक्तियों के प्रति हमारे कर्तव्य के प्रति सजग नहीं हैं, जिन्हें सार्वजनिक जीवन के इन क्षेत्रों से सामाजिक अथवा राजनैतिक कारणों से दूर रखा गया है।

तरजीह देने की जरूरत

इन सब मामलों में मेरा खुद का विचार यह है कि परिगणित जातियों तथा जन-जातियों जब तक सगठित न हो जायें और आवाज न उठाये तथा उन व्यक्तियों पर किसी हद तक लोकतांत्रिक दबाव न डाला जाय जोकि सेवाओं, काम-धंधों के सम्बन्ध में निर्णायक अधिकारी हैं तथा जिनके हाथ में अवसर है, तब तक वे सेवाओं में चाछित अनुपात में बिना किसी दिक्कत के तथा अधिकार के बतौर अवसर प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। इस दृष्टि से मेरा विचार यह है कि एक बिल्कुल स्पष्ट निर्देश के साथ इस सम्बन्ध में व्यापक व विस्तृत प्रवधान होना चाहिये कि कम से कम किसी वर्ष में सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रातिशत्य तक तो न्यूनतम योग्यता की शर्तों के साथ परिगणित जातियों तथा जन-जातियों के व्यक्तियों को तरजीह दी ही जानी चाहिये और इनके सिवाय दूसरी जातियों के लोगों को उस प्रातिशत्य की पूर्ति होने पर भर्ती किया जाय अर्थात् उस प्रातिशत्य में तो उक्त जातियों तथा जन जातियों के लोगों को ही लिया जाना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण जैसा है उसमें इन लोगों के कमी भी सार्वजनिक सेवाओं तथा वाणिज्य, व्यवसाय अथवा उद्योग में उस पैमाने पर अपना हक प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है कि उससे पूर्ण अथवा अर्ध बेरोजगारी की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ सके। उन व्यक्तियों ने जिन्हें ऐसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है सामाजिक दृष्टिकोण की जो

अपरिवर्तनशीलता दिमायी है, तथा उस समस्या के सम्बन्ध में उन्होंने जिस ढंग से काम किया है, सरकार को उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा।

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का महत्व

वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग स्थापित करने की समस्या से वित्त का सवाल भी सामने आयेगा। इस सम्बन्ध में विशेष कदम उठाने पड़ेंगे कि उधार सम्बन्धी कानूनों तथा नियमों आदि को इन लोगों की आवश्यकता के अनुसार ढाला जाय।

यह सब उन गैर-सरकारी अभिकरणों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता जोकि इन लोगों में काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का गांधीजी की तरह उचित मान्यता देकर सरकार एक बहुत अच्छा काम करेगी। यही एक मार्ग है कि हम सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की प्रतिष्ठा जमा सकेंगे और जिस प्रकार का काम वे करते हैं, उसे मान दे सकेंगे।

आवश्यक कदम

अतएव यदि हमें इन वर्गों के प्रति न्याय करना है और अपने शब्दों को कार्य रूप में परिणत करना है तो निम्न कदमों का उठाया जाना अपरिहार्य है

१ भूमि और जंगलों के सम्बन्ध में इन जन-जातियों के अधिकारों की रक्षा करना।

२ जहाँ-कहीं खेती के लायक जमीन उपलब्ध हो कृषि के लिए परिगणित जातियों तथा जन-जातियों के लोगों को जमीन देना।

३ घर बनाने के लिए इन दोनों ही वर्गों के लोगों को भूमि देना।

४ सरकारी सेवाओं अथवा सरकार द्वारा अनुदान और/या ऋण देने के रूप में सहायित सस्थाओं की

सेवाओं के मामले में ऊपर बताये अनगण्य व्यापक व विस्तृत प्रावधान रखना। इस प्रकार की व्यवस्था बिना किसी अपवाद के होनी चाहिये और सार्वजनिक सस्थाओं, सार्वजनिक अथवा निजी विभाग की सस्थाओं आदि को सरकार द्वारा अनुदान अथवा ऋण देने की यह एक शर्त होनी चाहिये, फिर चाहे उनका कार्यक्षेत्र चाहे कुछ भी क्यों न हो—चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, संस्कृति अथवा अन्य कोई।

५ उन्हें तकनीजों, कारीगरों के रूप में और औद्योगिक, वाणिज्य, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए दीर्घ स्तरीय सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये। नियक्तियों के लिए आवश्यक योग्यताओं के अलावा विशेष योग्यता शामिल करने के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना समाज का कर्तव्य होना चाहिये। यदि न्यूनतम योग्यताओं की शर्त पूरी होती है तो सम्बद्ध व्यक्ति को प्रवेश मिलना ही चाहिये। आगे का प्रशिक्षण भर्ती करने के बाद अथवा पहले सरकारी खर्च पर दिया जाय।

६ उन नियमों को रद्द किया जाना चाहिये जिनके लागू होने से परिगणित जातियों और जन-जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की पूर्ति कुछ समय के लिए नहीं हो पाती तथा वे खाली पड़े रहते हैं।

७ उन व्यक्तियों को उधार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये, जो व्यापार अथवा उद्योग के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं।

८ उन सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं तथा सामाजिक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, जो परिगणित जातियों तथा परिगणित जन-जातियों में काम करना चाहते हैं।

खादी कार्यक्रम और उसकी आलोचना

वैकुण्ठ ल. मेहता

प्रस्तुत लेख मे सार्वजनिक लेखा समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप समाचार-पत्रों में खादी कार्यक्रम की जो टीकाएँ हुई, उनको लेकर विचार किया गया है।

फरवरी के अन्त में सार्वजनिक लेखा समिति ने खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के हिसाब-किताब के बारे में ससद के सामने अपना प्रतिवेदन पेश किया। इससे खादी-ग्रामोद्योगों के विकास कार्यक्रम पर, जिसके कार्यान्वय हेतु कमीशन का गठन किया गया है, टीका करने का अवसर मिला है। जिस हद तक ये टीकाएँ सार्वजनिक लेखा समिति के पर्यवेक्षण और मालूमात से पैदा होती है, स्वयम् कमीशन ने उन पर अलग से विचार किया है। प्रस्तुत लेख उन सवालानों तक ही सीमित है, जो कि हाल ही में चन्द दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित लेखों के दौरान उठाये गये हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यह समीचीन ही होगा कि इन सवालों पर एक-एक कर अलग से विचार किया जाय।

सामाजार्थिक महत्व

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि 'एक राजनैतिक दल के सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो तो उसका प्रभार सार्वजनिक कोष पर क्यों पड़ना चाहिये?' स्पष्टतः यह धारणा है कि खादी के अधिकांश ग्राहक वे हैं जो कि या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं अथवा बनना चाहते हैं। यह सच है कि आजादी मिलने से पहले राष्ट्र ने गांधीजी को आजादी की लड़ाई में अपना नेता माना उसके बाद से खादी का विकास कांग्रेस कार्यक्रम का अंग रहा। तथापि, खादी आज कांग्रेस कार्यक्रम का कोई सजीव अंग नहीं है। न तो समाजवादी ढंग के समाजवाले अवाड़ी प्रस्ताव में ही और न भुवनेश्वर में पारित लोक-तांत्रिक समाजवाद के प्रस्ताव में ही 'खादी' शब्द का कोई

जिक्र है। पिछले दस वर्षों में, खादी के कभी भी जितने ग्राहक रहे हैं उनसे दस गुने उपभोक्ताओं को उमने अपनी ओर आकर्षित किया है। इन उपभोक्ताओं में कांग्रेस के सदस्यों अथवा सदस्य बनने के लिए खादी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत मामूली होगी। खादी की बिक्री कोई उनकी मदद पर निर्भर नहीं है।

क्या कमीशन बन्द कर देना चाहिये ?

इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न उठाया जाता है कि 'किसी दूसरे की खर्च के लिए कर-दाता क्यों भुगतें?' स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व के दिनों में खादी विकास कार्यक्रम राष्ट्र ने महात्मा गांधी की जिद्द या खर्च समझ कर नहीं अपनाया था। राजनैतिक क्षेत्र के महान कर्णधार राजाजी, लोह पुरुष सरदार पटेल, जवाहरलालजी, कृपलानीजी तथा अन्य ऐसे ही व्यक्तियों को किसी राजनैतिक निहितार्थ ने नहीं बल्कि इसके आर्थिक व सामाजिक महत्व ने आकर्षित किया था। योजना आयोग ने खादी और ग्रामोद्योगों के विकास कार्यक्रम को हमारी पंच वर्षीय योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया, तो उसके पीछे भी आयोग के गठन से लेकर अब तक ये ही विचार रहे हैं। योजना आयोग के सदस्यों में स्वर्गीय वी टी कृष्णमाचारी, श्री चिन्तामणि देशमुख, प्रोफेसर पी सी महालनोबीस जैसे कुछ व्यक्तियों का नाम यहाँ लिया जा सकता है, जो कभी कांग्रेसी अथवा अन्य किसी प्रकार के राजनीतिज्ञ नहीं रहे और उक्त निर्णय लेने में जिनका हाथ रहा है, जो कि यदि खादी 'किसी की खर्च' होती तो समर्थन नहीं करते।

यह विचार व्यक्त किया जाता है कि चूंकि पिछले दस वर्षों के प्रयासों के बाद भी खादी लोकप्रिय नहीं बन पायी है, जोकि इसके समर्थकों का दृढ़ उद्देश्य है, इसलिए एक निश्चित अवधि—उदाहरणार्थ तीन वर्ष—निर्धारित की जानी चाहिये कि उस अवधि में 'या तो वह कुछ प्रगति कर ले या फिर उसका काम बन्द कर दिया जाय'। उसी लेख के प्रारम्भिक भाग में (अखिल भारत) खादी और ग्रामोद्योग मण्डल से 'बड़ी गम्भीरतापूर्वक' कहा गया है कि 'वह अपना काम बन्द कर दे।' कानून में निश्चय ही केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से खादी और ग्रामोद्योग कमीशन का विघटन करने का प्रावधान है। अगर सरकार अथवा योजना आयोग यह समझे कि कमीशन की अब कोई उपयोगिता नहीं रही तो निस्सन्देह वह कदम उठाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से पूर्व अधिकारीगण कमीशन व उसके सलाहकारी मण्डल की सफलताओं का मूल्यांकन करेंगे। ये सफलताएँ प्रधान रूप से इस बात में निहित हैं कि उनकी प्राप्ति एक लाख से भी अधिक गावों के रहनेवाले २० लाख से ज्यादा लोगों को इस प्रकार के उत्पादक कामों में लगा कर रोजगारी का विस्तार करते हुए की गयी है कि उससे परमावश्यक उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आलोचक अपने आप से ही पूछ सकते हैं हमारी अर्थ-व्यवस्था में क्या कोई अन्य ऐसा क्षेत्र है जहाँ उक्त समय की समानान्तर अवधि में इतनी सख्या में लोगों को उत्पादक कार्यों में रोजगारी मिली हो।

कार्यक्रम का नव संस्करण

तथापि, आलोचक खादी कार्यक्रम के उस पक्ष पर जोर देते हैं जिसका केन्द्रीय सरकार अथवा योजना आयोग की दृष्टि में इस कार्यक्रम पर अपनी अनुमति देने में कभी कोई महत्व नहीं रहा। जैसा कि आलोचक सुझाते हैं उसके विपरीत, न तो यह कसैटी रखी गयी कि खादी को "ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था" की दिशा को प्रभावित करने के लिए एक आधार होना चाहिए" और न यह ही कि 'इसे लोक आन्दोलन बनाया जाय।' यह तो मण्डल

और कमीशन से सम्बद्ध तथा अखिल भारत चरखा सघ के पुगने कर्णधारों एवम् सर्व मेवा सघ की उत्साहपूर्ण भावना का ही फल है कि खादी-ग्रामोद्योग आन्दोलन के लिए उसे ग्रामीण समाज का कार्याकर्त्ता करनेवाला साधन बनाने का उच्च उद्देश्य रखा गया। उनके विचार से ग्राम्य समुदाय को आन्दोलन का भार सम्हालना चाहिये और एक बार उसे यानी ग्रामीण समुदाय को यह दिलजमी हो जाय कि यद्यपि कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन पूर्ण तथा अर्ध बेरोजगारों को रोजगारी प्रदान करना है तथापि कृषि-औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में चलाने पर उसमें खास तौर से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था एवम् सामान्य तौर पर ग्रामीण जीवन को प्रभावित करनेवाला महान प्रभाव छिपा है, तो वह उक्त जिम्मेदारी सम्हाल लेगा। यही वह दृष्टिकोण है जिसकी वजह से कमीशन ने कार्यक्रम का नव संस्करण करना आवश्यक समझा ताकि ग्रामीणों में अभिन्न, रुचि और उत्साह पैदा हो।

आत्मनिर्भरता का गुणार्थ

एक अन्य भारी अभियोग यह है कि खादी आगामी कुछ वर्षों तक आत्मनिर्भर बननेवाली नहीं है। इस मन्दर्भ में 'आत्मनिर्भरता' शब्द का सही गुणार्थ स्पष्ट नहीं है। और फिर, कोई यह भी पूछ सकता है कि क्या ससार के विभिन्न भागों में ऐसे देश नहीं हैं जहाँ राष्ट्रीय हित की दृष्टि से प्राथमिक कृषि उद्योग तक को उपदान अथवा वित्तीय सहायताएँ देकर जीवित रखा जाता है। फिर, कुछ ऐसे बहुत ही उद्योग-प्रधान देश भी हैं जहाँ राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कुछ प्रकार के दीर्घ स्तरीय उद्योगों को उपदान देना पड़ता है अथवा विदेशी स्पर्धा से उनकी रक्षा करनी पड़ती है। उन दस्तकारियों को भी विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो व्यक्ति की सृजन-शक्ति जिन्दा रखती है और लाभदायक काम प्रदान करती है। यदि खादी राष्ट्रीय योजनाओं का अंग है तो इसलिए नहीं कि २० करोड़ रुपये का सूती कपड़ा तैयार होता है, बल्कि इसलिए कि •

इस प्रकार का उत्पादन एक मूल्यवान सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। इस सन्दर्भ में 'आत्म निर्भर' शब्द का कोई महत्व नहीं है।

स्वदेशी की अपील

इस प्रकार इस आरोप का परीक्षण कि कार्यक्रम 'सहज रूप से ही दोषपूर्ण है', जिस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति वह करता है उसकी पृष्ठभूमि में करना पड़ेगा तथा इसलिए नहीं कि उद्योग "कभी भी अपने पैरो पर खड़ा होने की आशा नहीं कर सकता।" इस शताब्दी के प्रारम्भिक काल में स्वदेशी का पाठ पढ़ानेवाले राष्ट्र के अग्रणी नेताओं ने स्वदेशी उद्योगों की सहायता करने और उनके उत्पादन अपनाने के लिए जनता का आवाहन केवल उस वक्त तक के लिए ही नहीं किया था जब तक कि वे उद्योग अपने पैरो पर खड़े न हो जायें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि अपनी खरीद स्वदेशी उद्योगों के उत्पादनों तक ही सीमित रखी जाये, फिर चाहे कुछ त्याग ही क्यों न करना पड़े यानी उन उद्योगों की वस्तुएँ खरीदने में ज्यादा कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े अथवा उन उत्पादनों का गुण-स्तर निम्न कोटि का ही क्यों न हो। जन-मानस से यह अपील इसलिए नहीं की गयी थी कि उसमें विनियोजकों और उद्यमियों का हित है, बल्कि इसलिए कि अर्थ-व्यवस्था के विस्फुरण अर्थात् विकेन्द्रीकरण, रोजगारी के निर्माण और भूमि पर दबाव कम होने से राष्ट्रीय प्रगति की उद्देश्य-प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। औद्योगीकरण के लिए आयोजन करने के बावजूद, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में अवस्थित गतिहीनता की अवस्थाओं के रूप में गरीबी रूپی व्याधि अब भी मौजूद है।

यद्यपि देश में उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों प्रकार के सामान का वृद्धिशील परिमाण में उत्पादन हो रहा है, तथापि यदि कोई सार्वजनिक मामलों का उध्येता यह दावा करे कि अधिकांश ग्रामीण आबादी की अपने जीविकोपार्जन के लिए एक मात्र माधन के रूप में कृषि पर निर्भरता में कमी हुई है अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में

पूर्ण या अर्ध बेकारी की मात्रा घटी है अथवा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में विस्फुरण यानी विविधता आयी है, तो वैसा करना यदि उजड़ता नहीं तो एक प्रकार की धृष्टता ही होगी। सरकार ने खादी कार्यक्रम इसलिए स्वीकार किया है, क्योंकि अर्थ-व्यवस्था की इन बुराइयों को समाप्त करना उसकी जिम्मेदारी है और वह यह समझती है कि ऐसा करने के लिए उपभोक्ता सामग्री का ग्राम तथा कुटीर उद्योगों के जरिये उत्पादन करना एक सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग है।

श्रम विस्थापन

खादी आन्दोलन के कट्टर हिमायतियों ने भी कभी यह दावा नहीं किया है कि यह एक ऐसा उद्योग है, जिसके उत्पादन मिल वस्त्र से स्पर्धा कर सकते हैं। इसलिए आन्दोलन पर इस बात का लाञ्छन लगाना कि वह खादी की कीमत मिल कपड़े की कीमत के बराबर लाने में सफल नहीं हुआ है, शायद ही न्याय संगत हो। हाथ करघे के स्थान पर शक्ति करघा लगाने से पाँच-छ व्यक्ति विस्थापित होते हैं। चरखे की जगह 'कताई फ्रेम' लगाने से २५-३० कामगार विस्थापित होते हैं। कपड़ा मिलों में जो व्यक्ति 'कताई फ्रेम' अथवा शक्ति करघे लगाते हैं वे इस बात के प्रति उदासीन रहते हैं कि जिन व्यक्तियों की रोजी का जरिया छिन जाता है उन पर क्या गुजरती है। वे पारिश्रमिक पर श्रमिक रखते हैं। यह पारिश्रमिक हाथ से कताई या बुनाई करनेवालों के पारिश्रमिक से अधिक हो सकता है, तथापि, जिन व्यक्तियों को काम पर से निकाल दिया जाता है उनकी कुल आमदनी के बराबर किसी भी हालत में नहीं होता।

शारीरिक श्रम से चलाये जानेवाले तबूओं और करघों के स्थान पर शक्ति-चालित 'कताई फ्रेम' और करघे लगाने के रूपान्तरण की प्रक्रिया के पलस्वरूप विस्थापित होनेवाले इन व्यक्तियों को दिया जानेवाला यह पारिश्रमिक ही प्रधान रूप में मिल वस्त्र तथा खादी के उत्पादन खर्च में पाये जानेवाले भारी अन्तर का

कारण है। चूँकि मिल सूत का इस्तेमाल करनेवाले कच्चे के स्थान पर शक्ति-करघा लगाने से विस्थापन कम होता है, इसलिए हाथ करघा और मिल वस्त्र के मूल्य में अन्तर भी अपेक्षाकृत कम होता है। तथापि, चन्द प्रकार की हाथ करघा की भौतों और मोटी (कोर्स) खादी की कीमत में अन्तर कम है। इसके अतिरिक्त खादी अथवा हाथ करघा वस्त्रों के पोत की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं, जिनमें ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पिछले दस वर्षों में खादी के ग्राहकों की संख्या में जो दस गुनी वृद्धि हुई है, वह शायद ही हो पाती। मात्र प्रति रुपये २० नये पैसे की छूट के कारण ही शहरो और नगरों के निपुण ग्राहक खादी के एक-दो बार के नहीं बल्कि आदतन खरीदार नहीं बन गये हैं।

लागत संघटक

चूँकि उत्पादक लागत में पारिश्रमिक, खादी का उत्पादन खर्च निर्धारित करनेवाला एक प्रधान संघटक है, इसलिए आलाचक्रों का तर्क है कि “यदि वर्तमान अत्यन्त निम्न पारिश्रमिक” बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया गया तो उसका प्रभाव यह पड़ेगा कि खादी और भी महँगी हो जायेगी तथा वह अब की अपेक्षा मिल वस्त्र की स्पर्धा में बिकने के लिए और भी अयोग्य बन जायेगी। जिन व्यक्तियों के हाथ में कार्यक्रम का भार है उन्होंने अन्य सभी प्रकार के खर्च कम करने का उद्देश्य रखा है, उदाहरणार्थ कच्ची सामग्री की पूर्ति में, तैयार माल की बिक्री-व्यवस्था के संगठन के संबंध में अथवा बिना ब्याज के या बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के बारे में। परिणाम स्वरूप पिछले दस वर्षों की अवधि में रूई की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि होने के बावजूद खादी की अधिकांश भौतों की कीमत प्रायः एक-सी रही है। और, वस्त्रोद्योगी उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी रखनेवाले किसी भी व्यक्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उत्पादन की सफलता बहुत-कुछ रूई के गुण-स्तर पर ही निर्भर करती है। इस

सम्बन्ध में खादी उत्पादक को पिछले वर्षों के दौरान बहुत घाटे में रहना पड़ा है। छोटे रेशों की रूई से मध्यम तथा लम्बे रेशों की रूई अपनाने के सम्बन्ध में बड़ी तीव्र गति में परिवर्तन हुआ है, और हाथ कताई के लिए उपयुक्त किस्म की रूई की या तो कमी है अथवा फिर वह अनुपलब्ध है। जिस हद तक रूई महँगे भाव पर—यहाँ तक कि खादी की मोटी भौतों के लिए भी—खरीदनी पड़ी है, उस हद तक उत्पादन खर्च और भी बढ़ा है।

महात्मा गांधी ने जब उन्नत किस्म के चरखे के लिए एक लाख रुपये का पुरस्कार घोषित किया तो उनका दोहरा उद्देश्य था (१) सूतकार की आमदनी बढ़े, और (२) उत्पादकता बढ़ने के साथ कताई खर्च कम हो। उन्होंने परम्परागत चरखे तक की कुशलता बढ़ानी चाही थी, ताकि सूतकार अधिक कमाई कर सकें। अम्बर चरखा यद्यपि परम्परागत चरखे से ज्यादा कीमत-वाला और अधिक जटिल है, लेकिन उसमें गांधीजी के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करने की शक्यता है। सूतकारों की आय बढ़ी है, बुनाई-खर्च किसी हद तक कम किया जा सका है, खादी की कुछ भौतें ऐसी तैयार की जा चुकी हैं कि उनके और मिल के कपड़े की कीमतों में अन्तर किसी हद तक कम हुआ है। लेकिन रूई के भावों में जो वृद्धि हुई है उस कारण खादी के दामों में कोई खास कमी करना सम्भव नहीं बन पड़ा है।

शक्ति-प्रयोग के निहितार्थ

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने कुछ वर्ष पहले उन्नत चरखे के लिए पुरस्कार की घोषणा की थी। हाल ही में उसने वह अम्बर चरखा क्षेत्र में अपनाने का निर्णय किया है, जिसमें कम से कम एक रुपया दैनिक आमदनी प्रदान करने की क्षमता है। इससे पता चलता है कि खादी आन्दोलन में लगे कार्यकर्त्ता प्राविधिक प्रगति करने के प्रति सचेत हैं। यदि वे विकेन्द्रित आधार पर शक्ति का उपयोग करते हुए कताई करने की नहीं सोचते तो उनका यह दृष्टिकोण समझ में आने लायक है। अधिकांश खादी उत्पादन छोटे-छोटे गांवों में होता है।

इन्में से अधिकांश गाँवों तक निकट भविष्य में बिजली पहुँचने की सम्भावना नहीं है। एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की कल्पना उपलब्ध साधन-स्रोतों के सन्दर्भ में ही की जा सकती है। आज जो चीज उपलब्ध है, वह है असीमित जन-शक्ति। जब सबसे बड़ी आवश्यकता इस जन-शक्ति का पूर्ण उपयोग करने की हो तो खादी कार्यक्रमियों से शायद ही यह अपेक्षा की जा सके कि वे बिजली का इस्तेमाल करना अपनाये—खास कर तब जबकि बहुत कम गाँवों तक ही बिजली पहुँचनेवाली है। इसके अलावा उनके साथ सबसे बड़ी बात यह सुनिश्चित करना है कि बिजली का इस्तेमाल करने से जो जन-शक्ति हाथ कटाई में लगी है, वह निष्क्रिय न बन जाय। यदि काम के और कोई जरिये उपलब्ध होते तो उनका दृष्टिकोण भिन्न हो सकता था।

वस्त्रोत्पादन

अम्बर चरखे के प्रारम्भ से एक नयी सम्भावना सामने आयी है। ग्रामीण समुदाय के लिए अब यह बहुत सम्भव बन गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हाथ कटाई किये बिना अपनी आवश्यकता का कपड़ा तैयार कर सकता है। एक गाँव अथवा ग्राम समूह या क्षेत्र के लिए कपड़े के मामले में आत्म-निर्भर बनने का उद्देश्य रखना—खास कर वैसे स्थानों में जहाँ कपास की खेती होती है अथवा की जा सकती है—एक हो सकनेवाला काम बन जाता है। यही आदर्श गांधीजी प्रत्यक्ष देखना चाहते थे और इसी की पूजा आचार्य विनोबा भावे करते हैं। पुराने जमाने में हाथ कटाई ग्रामीण समुदाय का एक सहायक उद्योग था। आज हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उसके तुच्छ साधन-स्रोतों में दोहरा रिसाव है। ग्राम समाज इस सहायक धंधे के जरिये जो कुछ आमदनी कर पाता था, उससे वह हाथ धो बैठा। इससे भी अधिक यह कि उसे अन्यत्र उत्पादित वस्त्र की खरीद के लिए, जिसके उत्पादन में उसका कोई हिस्सा नहीं रहा, नकद की आवश्यकता पड़ी। अतएव विनोबाजी का विचार है कि ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था को

पुनर्स्थापित करने के लिए गाँव की भूमि के साम्य-मूलक वितरण कार्यक्रम के साथ बुनियादी उद्योग के रूप में हाथ कटाई और हाथ बुनाई का पुनरुद्धार करना एक परमावश्यक अंग होना चाहिये।

जन-शक्ति का लाभदायक उपयोग

आचार्य विनोबा भावे के अनुसार जिस प्रकार स्वेच्छा-पूर्वक साम्य-मूलक भूमि-वितरण के लिए एक आन्दोलन—भूदान आन्दोलन—है ठीक वैसे ही अर्थ-व्यवस्था को एक औद्योगिक अभिनति अथवा झुकाव प्रदान करने के लिए उन सभी व्यक्तियों के लिए मुफ्त बुनाई करवाने की व्यवस्था होनी चाहिये जो कातते हैं। ग्राम समाज को कुछ मामूली वास्तविक बंधे खर्च देने पर अपनी आवश्यकता का कपड़ा सूत की कीमत पर मिल जायेगा। खुद कातने-वाले को तो यह खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार के कदम का तिहरा प्रभाव पड़ेगा। प्रथम, यह अधिकाधिक लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए कातने को प्रेरित कर सकेगा, इससे कपड़े का स्थानीय बाजार विस्तृत होगा, और अन्तिम, इससे ग्राम समुदाय उन व्यक्तियों के लिए जो वर्ष में कई महीने अथवा दिन में अधिकांश समय बिना काम के रहते हैं, उत्पादक काम का सगठन करने में समर्थ बनेगा। तब ग्राम समाज, जन-शक्ति का परिपूर्णत लाभदायक रूप में उपयोग करने का काम हाथ में ले सकता है। इस प्रकार जबर्दस्ती की निष्क्रियता को जड़ से काटा जा सकेगा, जोकि समाज-व्यवस्था में एक क्षयकारी शक्ति है। इस प्रकार उपदानित बुनाई का सूतकार और बुनकर को प्रत्यक्ष तथा शेष समाज को परोक्ष लाभ प्राप्त होगा।

उत्पादन-स्तर पर उपदान, बिक्री-स्तर पर की छूट का स्थान लेता है। लेकिन उपदान का लागत पर प्रभाव इस प्रकार का होगा कि अन्य सब खर्च जैसे-कैसे रहते हुए भी उत्पादन का बिक्री-मूल्य कम हो। इस प्रकार शहरी ग्राहकों को उसी कीमत पर खादी मिलती रहेगी जिम पर अब तक मिलती रही है, और इस आधार पर बिक्री में कोई कमी नहीं आनी चाहिये, क्योंकि खादी

के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। और फिर, अधिक अनुदान के लिए जन-कोप में कोई अतिरिक्त मांग नहीं की जायेगी, क्योंकि आवश्यक सहायता के परिमाण का अनुमान उतना ही है जितना कि फिलहाल।

हैं, उत्पादन विस्तार से अवश्य परिचय्य बढ़ सकता है। इस भय में कोई विशेष दम नहीं है कि उत्पादन स्तर पर उपदान देने से भ्रष्टाचार की गुजाइश बढ़ जायेगी। यह सच है कि जिन केन्द्रों पर उपदान दिया जायेगा, उनकी सख्या विक्री-केन्द्रों की सख्या से ज्यादा होगी। फिर भी, उपदान के भुगतान पर नियंत्रण रखना अथवा हिमाव-किताब की जाँच करना अब की अपेक्षा कोई ज्यादा कठिन नहीं होगा।

सामाजिक सुरक्षा

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका उद्देश्य है खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रस्तावित नव सस्कृत खादी कार्यक्रम का एक युक्तियुक्त विवरण प्रस्तुत करना। जैसा कि एक पत्र में कहा गया है उसके विपरीत, खादी आज मात्र 'निष्ठा' की चीज नहीं है, और न ही वह जैसा कि एक अन्य पत्र ने कहा है, "एक अपव्ययपूर्ण तथा अनुत्पादक कार्यक्रम है, जिसमें करदाता का पैसा बर्बाद किया जा रहा हो।" पिछले दस वर्ष में—भूतकाल में अखिल भारत चरखा सघ द्वारा की गयी

अमूल्य सेवाओं के अतिरिक्त—जो सफलताएँ प्राप्त की गयी हैं वे खादी ने, हमारे विदेशी शासकों की आर्थिक नीतियों तथा अनियंत्रित औद्योगीकरण की चोट से बुरी तरह घायल देहाती क्षेत्रों के एक बुनियादी उद्योग को जिन्दा रखते और पुनः अनुप्राणित करने हुए, राष्ट्र की प्रगति में जो योगदान दिया है उसका प्रमाण है।

पूर्ण तथा अर्ध-बेकारी की समस्याएँ आज उस वक्त से भी भयानक हैं जब महात्मा गांधी ने ४५ वर्ष पूर्व खादी उद्योग के पुनरुद्धार निमित्त कार्यक्रम बनाया था। इस प्रकार की बेरोजगारी में राहत पाने के लिए अन्य देशों ने अधिक वर्चस्वी योजनाएँ चलायी हैं। उद्योगों में संगठित श्रमिकों के सीमित अंश को छोड़ कर हमारे यहाँ ऐसी कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है कि उसके अन्तर्गत बेरोजगारी में राहत देने की कोई व्यवस्था हो। सामाजिक सुरक्षा की एक परिपूर्ण योजना के अभाव में, इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए नियत धन राशि को एक अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना पर खर्च रहस्य के रूप में देखना चाहिये, जिसके अन्तर्गत आबादी का एक बहुत बड़ा नाजुक हिस्सा आता है तथा उसका तब तो और भी अधिक स्वागत होना चाहिये जबकि वह योजना उनकी दान देने के स्थान पर काम देकर सहायता करती हो।

बम्बई . १२ मार्च १९६४

किसी पिछड़े देश के जड़ता रूपी अवरोधों पर काबू पाने, जन-मानस को प्रज्वलित करने और लोक-शक्ति को आर्थिक विकास में प्रयुक्त करने के लिए साधन-स्रोतों के बेहतरीन वितरण तथा कम दाम में रोटियों प्रदान करने के वादों से भी बढ़ कर तेज दवा की जरूरत है। ऐसी अवस्थाओं में व्यापारी वर्ग तथा दुस्साहसी उद्यमियों को भी उच्च लाभ की बनिस्पत कोई अधिक शक्तिशाली प्रेरणा देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। रोजमर्रा के 'छटीन' और अन्य-मनष्कता के पहाड़ को पार करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है—सन्त साइमन के शब्दों में उस विश्वास की कि 'सोने के अण्डे आदमी के पीछे नहीं, आगे हैं।'।

—अलेक्जेंडर गरशेक्रोन इक्नॉमिक बैकवर्डनेस इन हिस्टोरीकल पर्सपेक्टिव, दि वेलकनाप प्रेस, कैम्ब्रिज, मॅसॅचुसेट्स।

ग्रामोद्योगों के लिए मध्यम प्रौद्योगिकी*

त्रिभुवन नारायण सिंह

मध्यम प्रौद्योगिकी कोई स्थिर प्रतिमान नहीं है। वह एक चर औसत से अधिक मिलती है, जो एक आगे बढ़ रहे समाज में प्राविधिक परिवर्तन-दर को प्रतिबिम्बित करती है। बढ़ती हुई अपेक्षाओं और नयी पीढ़ी के लोगों में अपने पुश्तैनी व्योक्तों के प्रति कोई विशेष रुचि न होने की वजह से मध्यम प्रौद्योगिकी को एक बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। इसे सस्ती और उत्पादक दोनों प्रकार की होना पड़ेगा कि विनियोजन के लिए अधिक बचत की माँग न करे तथा साथ ही स्वीकार्य अर्थात् समुचित आय भी प्रदान कर सके।

लघु उद्योगों और खास कर ग्रामोद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के उपयुक्त स्तर की समस्या पर सोचने तथा चर्चा करने की दिशा में इस बैठक का एक विशेष महत्व है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त ग्रामीण उद्योग समिति और उसकी स्थायी समिति एक वर्ष से अधिक हो गया कि इस विषय पर ध्यान दे रही है। इसके विभिन्न पक्ष परीक्षण और सामान्य विचार-विमर्श के लिए सामने आये हैं। अनिवार्यतः चर्चा को सामान्य विचार और मोटा-मोटी उपागम से आगे बढ़ा कर ठोस विस्तृत बातें तैयार करने तथा व्यावहारिक प्रयोग के सवाल-जवाब तक लाना आवश्यक था। विचार की परिशुद्धता प्राप्त करने और तद्विषयक विभिन्न बातों को गहराई से समझने, परखने के लिए यह महसूस किया गया कि एक छोटे, लेकिन विशिष्ट समूह में गहन विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

ग्रामीण रोजगारी के लिए कार्यक्रम

देश में बेरोजगारी की दुर्दम समस्या के समाधान के प्रति अपने उपागम में योजना आयोग ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की कल्पना की है। प्रथम कार्यक्रम

गाँवों में उपलब्ध निष्क्रिय जन-शक्ति का उपयोग करते हुए सामूहिक सम्पत्ति का निर्माण करने से सम्बन्धित है। दूसरे कार्यक्रम में इस बात का सुझाव है कि 'मध्यम प्रौद्योगिकी' (इण्टरमीडियट टेक्नोलॉजी) अपनाते हुए देहाती क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाय। प्रथम कार्यक्रम इस विचार पर आधारित है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद का बेरोजगारी की हालत में होना मौसमी स्वरूप का है और वह उत्पादक कामों में लगने की प्रतीक्षा में है। इसलिए जिन इलाकों को पिछड़े क्षेत्र समझा जाता है, उनमें विस्तृत निर्माण कार्यक्रम चलाने का परिणाम यह निकलेगा कि गाँवों में कम से कम वर्ष में एक सौ दिन बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिल सकेगा। ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्राम्य क्षेत्रों में लोगों को काफी तादाद में पूर्ण रोजगारी प्रदान करना और, इस प्रकार हमारे लाखों-करोड़ों ग्रामवासियों का जीवन सार्थक बनाना तथा फलस्वरूप उन्नत उत्पादन तकनीकें अपना कर मानव एवम् सामग्री के रूप में उपलब्ध साधन-स्रोतों का अधिक लाभदायक रूप में उपयोग करना।

यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि यद्यपि दोनों ही कार्यक्रमों से ज्यादा रोजगारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तथापि, पूर्ण रोजगारी स्वयम् में कोई साध्य नहीं, बल्कि साध्य तक पहुँचने का साधन है, और वह साध्य है अधिक राष्ट्रीय उत्पादन तथा आर्थिक विकास

* दिनांक २ जनवरी १९६४ को हैदराबाद में सम्पन्न मध्यम प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यकारी दल की बैठक में दिये गये उद्घाटन भाषण से। विचार-गोष्ठी का आयोजन हैदराबाद स्थित लघु उद्योग विस्तार प्राशिक्षण संस्था ने किया था। गोष्ठी २ में ४ जनवरी तक चली।

की तीव्र गति शामिल करना। ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से सच है। जिस प्रकार के काम में भारत के गरीबों की रुचि है, वह ऐसा काम है जिससे अधिक काम और ज्यादा रोजगारी को प्रश्रय मिले, इस तरह के काम में नहीं जो कुछ समय बाद उन्मूलित हो जाय। इसलिए योजना आयोग देश भर के चुनिन्दा क्षेत्रों में चल रही मार्गदर्शी परियोजनाओं को सर्वाधिक महत्व देता है, क्योंकि यदि ये परियोजनाएँ सफल रही तो उनसे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का कायाकल्प होना चाहिये।

श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी

आज गांव का कोई बेरोजगार व्यक्ति आंगिक काम अथवा कर्म पारिश्रमिक में भी मन्तुष्ट नहीं होगा। उसे एक उपयुक्त आय का आश्वासन मिलना ही चाहिये। और उसके लिए उच्च उत्पादन स्तरवाली बेहतरीन प्रौद्योगिकी का होना आवश्यक प्रतीत होता है। इस कार्यक्रम का प्रत्ययवचन होना चाहिये 'श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के जरिये अधिक उत्पादन और पूर्ण रोजगारी।' हमें निवेश अवरोधक गरीबी और गरीबी को स्थायी बनाने-वाले निम्न विनियोजन के दुष्प्रभाव को भिड़ाना होगा। मेरे विचार से ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम यदि सफल हुआ तो उससे इसका समाधान मिलना और यह दुष्प्रभाव भिड़ाना चाहिये।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में 'मध्यम प्रौद्योगिकी' का सम्बोधन एक माने में नया है और उसके निहितार्थों को समझना अभी बाकी है। अभी तक वह व्यावहारिक उपयोग में नहीं आया है और आयोजक तथा नीति निर्धारक वर्ग की प्रामाणिकता के बिना अगर उसे प्रचलित किया गया तो उसकी ओर नजरे उठ सकती है। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि आप लोग इस कार्यकारी दल में अपने विचार-विमर्श के प्रारम्भिक स्तर पर इस 'पद' को यथार्थ गुणार्थ प्रदान करेंगे और हमारे सामने जो समस्याएँ हैं उनके विश्लेषण में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे। 'मध्यम' शब्द समोत्कर्ष रूप में एक सापेक्षिक

'पद' है तथा एक ओर वह किसी उच्च अथवा उन्नत और दूसरी तरफ किसी निम्न अथवा पिछड़ी हुई चीज से जुड़ा हुआ है। अतः आप के लिए इन तीनों 'पदों' पर एक माय विचार करना और भारत में पाई जानेवाली अवस्थाओं के सन्दर्भ में 'मध्यम' शब्द की सीमा परिभाषित करना आवश्यक हो सकता है।

मैं परिभाषाओं का पुजारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन्हें विचारोपकरण समझता हूँ। बाल की खाल निकाल कर उन्हें इतना परिष्कृत नहीं कर देना चाहिये कि वे अपना व्यावहारिक प्रभाव ही खो बैठें। अगर कोई परिभाषा न हो तो एक काम चलाऊ परिभाषा निश्चय ही अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही वह काम चलाऊ परिभाषा एक बहुत ही परिष्कृत और शास्त्रीय परिभाषा के प्रायः समान ही होता है।

ग्रामीण उद्योग परियोजनाएँ

तथापि, मैं इस विषय के एक भिन्न पक्ष का जिक्र करना चाहूँगा, जो कि मेरी दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग एक वर्ष पूर्व योजना आयोग ने ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम प्रवर्तित किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के सचन विकासार्थ देश के सभी १५ राज्यों और चार केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में ४५ क्षेत्रों का चुनाव किया गया। इनमें से प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत तीन से पाँच तक विकास खण्ड आते हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य या क्षेत्रीय-प्रत्यक्ष-अनुभव के जरिये ग्रामीण औद्योगीकरण के देशव्यापी कार्यक्रम के लिए आधार ढूँढ निकालना। इस प्रयास के पीछे निहित विचार यह है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का कृषि-औद्योगिक सन्दर्भ में विकास किया जाय, उसका आधार विस्तृत किया जाय कि उसमें लघु उद्योग शामिल किये जा सकें और यह कि कृषि क्षेत्र से बाहर काम के अवसरों का निर्माण करने के लिए भूतकाल में जैसे प्रयास सम्भव थे, उनसे अधिक सोद्देश्य प्रयास किये जायें। औद्योगिक विकास की सम्भाव्यताओं का पता लगाने और विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए

पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध में वड़ी तीव्र गति से सर्वेक्षण किये गये। सर्वेक्षणों के मालमातो और निष्कर्षों पर जुलाई १९६३ में योजना आयोग द्वारा आयोजित दो सम्मेलनों में विचार किया गया तथा तत्पश्चात् राज्य सरकारों से कार्यक्रम बनाने एवम् कार्यान्वित करने के लिए कहा गया। कुछ राज्यों में यह काम शुरू हो चुका है।

प्रौद्योगिकी के स्तर का चयन

ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व खादी और ग्रामीण कमीशन, सामुदायिक विकास औद्योगिक मार्गदर्शी परियोजनाओं तथा ग्राम व लघु उद्योगों सम्बन्धी अन्यान्य कार्यक्रमों के जरिये अर्जित ज्ञान एवम् अनुभव का पूर्ण लाभ उठाया गया। फिर भी, यह स्वीकार किया गया कि ग्रामीण औद्योगीकरण में कठिनाइयाँ तथा समस्याएँ हैं और प्रारम्भिक तौर पर उसे प्रायोगिक पैमाने पर चलाया जायेगा। एक प्रमुख सवाल यह था कि हमारा जो वर्तमान विकास स्तर है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए किस प्रकार की और किस स्तर की प्रौद्योगिकी अपनायी जाय।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि प्रौद्योगिकी विषयक सवालानों को आर्थिक तथा सामाजिक सन्दर्भ से अलग करके, उन्हें अलगाव की स्थिति में रख कर विचार नहीं किया जा सकता। जिस ढंग की प्रौद्योगिकी हमें अपनी हो उस पर जिस ढंग का समाज हम निर्मित करना चाहते हैं, उससे अलग करके नहीं सोचा जा सकता। सामाजिक पुनर्निर्माण का मोटा-मोटी उपागम हमें अपने सर्वज्ञान, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त, औद्योगिक नीति विषयक प्रस्ताव, समाजवादी ढंग के समाज के सिद्धान्तों और पंच वर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में मिलता है। उनमें निहित बातें सर्व विदित हैं और उन पर पुनः कुछ कहने की शायद ही जरूरत हो। फिर भी यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या चित्र पर्याप्त रूपेण स्पष्ट है और क्या यह कार्यकारी दल अन्य कोई सवाल उठाये बिना ठोस मान्यताओं के साथ आगे बढ़ सकता है?

उदाहरण के लिए उद्योग के विकेन्द्रित विकास का सवाल अभी तक पूर्ण रूप से हल नहीं किया जा सका है कि किस पैमाने पर और किन उद्योगों में इस प्रकार का विकास किया जाना चाहिये तथा क्या समूची अर्थ-व्यवस्था देश भर के सहस्रो गाँवों एवम् शहरों में विस्तृत रूप से फैली हुई उद्योगों की छोटी-छोटी कार्य-क्षम इकाइयों पर आधारित होनी चाहिये? इस प्रश्न के प्रति वर्तमान उपागम 'सामान्य उत्पादन कार्यक्रम' के अर्थात् दीर्घ अवधि केन्द्रित विभाग और लघु अवधि के विकेन्द्रित विभाग के सह-अस्तित्व की स्थिति के अनुरूप है। इस सम्बन्ध में १९५६ के औद्योगिक नीति विषयक प्रस्ताव का यह अंश यहाँ प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा "राज्य दीर्घ स्तरीय विभाग का उत्पादन सीमित रखने अथवा विभेदात्मक कराधान लगाते या प्रत्यक्ष उपदान देते हुए कुटीर तथा ग्राम और लघु उद्योगों को मदद देने की नीति का अनुसरण कर रहा है। जबकि इस प्रकार के उपाय—जहाँ-कहीं आवश्यक हुआ—काम में लाये जाते रहेंगे, वहाँ राज्य नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि विकेन्द्रित विभाग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ले तथा उसका विकास दीर्घ स्तरीय उद्योगों के विकास के साथ सुसंयोजित हो। इसलिए राज्य लघु स्तरीय उत्पादक की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार के लिए बने उपायों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके लिए उत्पादन तकनीकों में सुधार करना और उन्हें आधुनिक स्वरूप देना, यथा संभव प्रौद्योगिक बेरोजगारी से बचने के लिए रूपान्तरण की गति नियंत्रित रखना परमावश्यक है।"

मध्यम प्रौद्योगिकी

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की सोद्देश्य नीति के इन तत्वों पर पंच वर्षीय योजनाओं में भी जोर दिया गया है। यह सवाल पूछना और उसका उत्तर देना सगत होगा कि उस समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना उपयुक्त होगा, जो वैसे पारिश्रमिक पर अपने गाँवों तथा कस्बों में अधिकाधिक गैर-खेतिहर रोजगारी

का निर्माण करना चाहता है, जो एक उपयुक्त जीवन स्तर बनाये रखने तथा कुछ बचत भी करने के लिए योग्य हो। प्रौद्योगिकी स्तर और जन-शक्ति के परिपूर्ण उपयोग के सम्बन्ध का अध्ययन करना एक सम्बद्ध पहलू होगा।

यहाँ मैं उपागम के एक अन्य प्रकार का जिक्र कर सकता हूँ, जिस पर सम्भवतः अपनी चर्चा के दौरान आप विचार करना पसंद करें। यह स्वयम् सिद्ध है कि एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था और परिवर्तनशील समाज में प्रौद्योगिकी के स्तरों में भी अनवरत परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब है कि 'मध्यम प्रौद्योगिकी' कोई स्थिर प्रतिमान नहीं है, यह एक चर औसत से अधिक मिलती है, जो एक आगे बढ़ रहे समाज में प्राविधिक परिवर्तन दर को प्रतिबिम्बित करती है। इस दृष्टि से विचार करने पर 'मध्यम प्रौद्योगिकी' एक तरल विचार जैसी वस्तु लग सकती है, उसे कोई निश्चित स्वरूप नहीं दिया जा सकता कि यही 'मध्यम प्रौद्योगिकी' है तथा उसे निरन्तर नया स्वरूप देते रहने की आवश्यकता है। इस सम्बोध की दीर्घ कालीन दृष्टि से उपयोगिता रहेगी अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि इसे किन तत्वों अथवा विशिष्टताओं में कसा एवम् परिभाषित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी, निवेश व पारिश्रमिक

एक साधारण विशिष्टता यह सुझायी गयी है कि प्रति कार्य स्थल पर उपकरणों पर कितना पैसा लगता है। ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति को भेजे गये अपने 'पेपर' में डाक्टर ई. एफ. शमेखर (Schumacher) ने एक काम चलाउ औसत १,००० रुपया सुझाया है। उन्होंने यह अंक विस्तृत ग्रामीण औद्योगीकरण की विशालता और अध्ययन के लिए प्रारम्भिक बिन्दु के तौर पर सुझाया है।

जहाँ कुछ उद्योगों में अचल पूँजी निवेश प्रौद्योगिकी स्तर का एक अच्छा निर्देशक है, वहाँ मुझे ऐसा लगता कि कुछ अथवा उद्योगों में संचालन पूँजी कितनी ही अधिक महत्वपूर्ण है तथा उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि प्रति कार्य-स्थल अथवा प्रति कर्मी विनि-

योजित पूँजी की कुल रकम भी हो सकता है सन्तोषप्रद कसौटी प्रदान न कर सके, यदि उससे प्राप्त पारिश्रमिक दर न्यूनतम के अनुरूप न हो, जोकि व्यक्ति को अपनी बचत का अथवा विकल्प स्वरूप सरकार, किसी बैंकिंग संस्था, साहूकार या मित्र से उधार लेकर विनियोजन करने को प्रेरित करेगा। अनेक बेरोजगार आदमियों का उस उद्योग में काम करने के लिए तैयार न होने की सम्भावना को टाला नहीं जा सकता, जिसमें उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप पारिश्रमिक न मिले, फिर चाहे उस उद्योग में उन्हें अपना खर्च का कुछ भी विनियोजन न करना पड़े। बढ़ती हुई अपेक्षाओं और नयी पीढ़ी के लोगों में अपने पुश्तैनी धर्मों के प्रति बेकम आय देनेवाले होने की वजह से कोई विशेष रुचि न दिखायी देने के कारण 'मध्यम प्रौद्योगिकी' को एक कठिन परीक्षा में उन्नीर्ण होना पड़ेगा। इसे सस्ती और उपादक दोनों प्रकार की होना पड़ेगा कि विनियोजन के लिए अधिक बचत की माँग न करे तथा साथ ही स्वीकार्य अर्थात् समुचित आय भी प्रदान कर सके।

प्रत्येक उद्योग व क्षेत्र के लिए

इस प्रकार की प्रौद्योगिकी की क्षमता के सामने एक ओर स्तरीय रोजगारी प्रदान करने तथा दूसरी ओर पर्याप्त रूपेण उत्पादक होने की उतनी ही कड़ी परीक्षा और है। सम्भवतः हो सकता है कि कौशल उपलब्धि को 'मध्यम प्रौद्योगिकी' का निर्धारण करने में एक अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार करना आवश्यक न हो, क्योंकि विस्तृत कार्यक्रम के जरिये कौशल-प्रशिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन लघु काल में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल-स्तर ऐसा है, जिस पर ध्यान दिये बिना नहीं रहा जा सकता। दूसरा प्रासंगिक पक्ष है देश के भीतर ही 'मध्यम प्रौद्योगिकी' के अनुरूप उपकरणों का निर्माण करने की संभावना, क्योंकि स्पष्टतः एक व्यापक व विशाल ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम यंत्रों तथा उपकरणों के दीर्घ स्तरीय आयात पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये विशिष्टताएँ अथवा तत्व 'मध्यम प्रौद्योगिकी' के लिए मात्र रूप-रेखा ही प्रस्तुत करते हैं। मुख्य बात तो अगर

यह प्रौद्योगिकी कही है तो उसे पहचानने और ढूँढ निकालो तथा अगर नहीं है तो उसकी डिजाइन बना कर एवम् निर्माण करके प्रतिष्ठापित करने की है। दोनों ही मामलों में विस्तृत क्षेत्र में प्रयास करने पड़ेंगे और वह भी प्राविधिक सम्भाव्यताओं की घबरा देने वाली विधिका के साथ। प्रत्येक उद्योग और क्षेत्र के लिए 'प्रौद्योगिकी' का स्तर पहचानना, ढूँढना अथवा निमित्त करना होगा। असंख्य सचय तथा क्रमचय करने पड़ेंगे। इस तथ्य से और भी जटिलता पैदा हो सकती है कि कुछ उद्योगों में 'मध्यम प्रौद्योगिकी' का सवाल हो सकता है उपकरणों के इस्तेमाल का उतना न हो जितना कि नयी प्रक्रिया के अथवा उत्पादक सघटकों के भिन्न सचय के उपयोग का। तथापि, मैं यह कदापि नहीं सुझाना चाहता कि इस काम की कोई कीमत नहीं है और इससे योग्य तकनीकों को अपने प्रयासों का प्रतिफल नहीं मिलेगा।

सघन अन्वेषण आवश्यक

बड़े-बड़े कामों की शुरूआत कभी-कभी मामूली हुआ करती है और हो सकता है कि कार्यकारी दल शायद चयनकारी उपागम अपनाता पसन्द करे तथा इस सम्बन्ध में प्रारम्भ के तौर पर सघन अध्ययन के लिए कुछ उद्योगों व क्षेत्रों का चुनाव करे। ये उद्योग ऐसे हो सकते हैं, जिनका ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम की प्रारम्भिक अवस्था में प्रमुख स्थान होनेवाला हो। चुनिन्दा उद्योगों में व्यवहृत उपकरणों तथा प्रक्रियाओं, प्रति नियुक्त व्यक्ति व जी विनियोजन, प्रयुक्त कौशल के स्तर, पारिश्रमिक आदि के सम्बन्ध में आकड़े इकट्ठे करने के लिए

गहन अध्ययन व अन्वेषण करना आवश्यक हो सकता है। उद्देश्य होगा 'मध्यम प्रौद्योगिकी' के सर्वाधिक निकट प्रौद्योगिकी की खोज, फिर उसकी परिभाषा चाहे जो भी हो। यदि इस प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो तो उस अवस्था में अगला कदम होगा उपकरणों को लोकप्रिय बनाना तथा उनके परिमाण में वृद्धि करना। यदि प्रौद्योगिकी नहीं हुई तो वैसी अवस्था में उपकरणों-त्पादन अथवा प्रक्रिया निर्माण की समस्या पर अभियन्ताओं, वैज्ञानिकों और औद्योगिक नमूनाकारों (डिजाइनर) का मत जानना होगा। द्वितीय अवस्था में दो वैकल्पिक उपागम हो सकते हैं या तो लघु उद्योगों के लिए नये उपकरणों के नमूने तैयार करके उनका निर्माण किया जा सकता है अथवा फिर बड़े उद्योगों में प्रयुक्त उपकरणों का छोटा रूप तैयार किया जा सकता है अथवा लघु स्तरीय उत्पादन के लिए उपयोगार्थ उन्हें अनुकूल बनाया जा सकता है। मात्र उदाहरण के तौर पर मैं यह कह सकता हूँ कि रईस सामग्री के उपयोग, रेशा प्रशोधन तथा तकुआ इकाई बनाने की सम्भाव्यताएँ हैं। वस्तुतः यह कार्य मनोहरी तथा चुनौतीपूर्ण दोनों प्रकार का है।

इस काम में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, आविष्कार प्रोत्साहन मण्डल, प्रौद्योगिकी संस्था तथा इंजीनियरिंग कालेज और विश्वविद्यालयों सहित अनेक सगठनों का ध्यान और कर्मचारियों को लगाना पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों का सहकार प्राप्त करना होगा।

हमारे नये टेलीफोन नम्बर

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के विले पार्ले (बम्बई) स्थित केन्द्रीय कार्यालय के टेलीफोन नम्बर बदल गये हैं। नये टेलिफोन नम्बर इस प्रकार है ५७१३२४, ५७१३२५, ५७१३२६, ५७१३२७, ५७१३२८ और ५७१३२९।

लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी¹

दया कृष्ण मल्होत्रा

समुचित प्रौद्योगिकी क्षेत्र, उद्योग तथा विशेष परिस्थितियों के अनुसार उन्नत, मध्य या निम्न स्तरीय हो सकती है। बहुत से लघु उद्योगों पर ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नो वृद्धि की सम्भावनाएँ हैं, विशेष रोज के लिए एक छोटा विश्लेषण तथा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है और वहाँ के परिणामों को सिर्फ आयोजन और नीति निर्धारक मन्त्रालयों के बीच ही नहीं, बल्कि एक प्रौद्योगिक सूचना और विस्तार सेवा केन्द्र के जरिये औद्योगिक मन्त्रालयों तथा निजी क्षेत्र के छोटे उद्योगपतियों के बीच भी प्रसारित किया जा सकता है।

उद्योग, छोटा हो या बड़ा, बुनियादी तौर पर कच्चे मालों का रूप-परिवर्तन है और उसमें जो प्रक्रिया होती है, उससे कच्चे माल की उपयोगिता बढ़ जाती है। कच्चे माल को किसी अन्य रूप में बदल देने का कोई दूसरा दैवी या गैबी तरीका नहीं है। यह परिवर्तन इसलिए आवश्यक है कि उपभोक्ता तैयार वस्तुओं को अधिक उपयोगी पाता है और उसके लिए अधिक मूल्य देने को राजी होता है। ग्रामीण (या शहरी) क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के औचित्य का आधार उपभोक्ताओं की यही माँग होनी चाहिये, न कि ग्रामीण (या शहरी) औद्योगीकरण की कोई तुल्यकामिजाजी, शौक या नारे-बाजी। रूप-परिवर्तन की प्रक्रिया, कितनी दक्षता और मितव्ययिता के साथ चलायी जाती है, यह निर्भर करता है इस बात पर कि किस तरह की प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) अपनायी गयी है। यह प्रौद्योगिकी उच्च, मध्यम और प्रारम्भिक कोई भी हो सकती है। यह स्पष्ट है कि अगर कोई दूसरी समस्याएँ नहीं हैं, तो सर्वाधिक दक्ष और आर्थिक तौर पर दुरुस्त प्रौद्योगिकी अपनायी जा सकती है। किन्तु रोना भी तो यही है कि अन्य समस्याएँ भी हैं और वैसे अवस्था में सर्वाधिक आसान और पूर्णतः तर्क संगत समाधान कोई आवश्यक नहीं कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक व्यावहारिक ही हो।

पहली बात, हो सकता है कि सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पर्याप्त पूँजीगत साधनों की उपलब्धि न हो। प्रत्येक प्रकार की प्रौद्योगिकी के

लिए कुछ न कुछ विनियोजन की आवश्यकता पड़ती है और अधिक उन्नत तथा जटिल के लिए तो आम तौर पर बड़े विनियोजन की आवश्यकता होती है। अगर उपलब्ध पूँजीगत साधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत कर सके तो यह स्वाभाविक है कि देश को कुछ नीचे स्तर की प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ेगी, जो बहुत ही निम्न स्तर की या बहुत किस्म की न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी पर विचार करने में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किसी खाम किस्म की प्रौद्योगिकी को बहन करने के लिए क्या पूँजीगत साधन उपलब्ध है?

कृषि से सम्बन्ध

पर्याप्त पूँजीगत साधनों की उपलब्धि अगर हो भी गयी तो हम सिलसिले में दूसरा सवाल उठेगा कच्चे माल की उपलब्धि का। यत्रो को साल भर चालू रखने के लिए अगर पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है तो उन्नत प्रौद्योगिकी का चयन सबसे अच्छा होगा। किन्तु इसके विपरीत, किसी क्षेत्र में उपलब्ध कच्चा माल अगर महज चन्द दिनों के उपयोग भर का हो तो उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने से ऐसी समस्याएँ उठेंगी कि यत्र बन्द हो जायेंगे और उसके परिणाम-स्वरूप कर्मचारियों एवम् व्यवस्था के समक्ष भी कोई काम करने को नहीं रहेगा। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे माल की प्राप्ति अधिकांशतः कृषि और पशु-पालन से होगी, इसलिए कच्चे माल की प्राप्ति का विस्तार निर्भर करेगा कृषि-पशु-पालन सघटन की प्रौद्योगिक दक्षता पर। इससे एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की प्रौद्योगिकी पर कृषि-औद्योगिकी से अलग रह कर विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस

* मध्यम प्रौद्योगिकी विषयक कार्यकारी दल की हैदराबाद में २ जनवरी १९६४ को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत 'पेपर'।

बात को कभी-कभी नजरदाज कर दिया जाता है या उसके महत्व को कम समझा जाता है। दोनों के बीच किसी प्रकार की समानता स्थापित करनी ही होगी, नहीं तो उन्नत या मध्यम प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने-वाले लघु उद्योगों के ढाँचे के निर्माण में कृषि के साथ उनके सम्बन्धों में वे ही दिक्कतें और परेशानियाँ पैदा होंगी जो गाड़ी खींचनेवाले बैलों की जोड़ी के स्थान पर स्वचलित इंजन के आ जाने से बैल गाड़ियों के सम्बन्ध में पैदा हो गयी है। इसीलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि ग्रामोद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी पर विचार करते समय कृषि व लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी के पारस्परिक सम्बन्धों पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

कच्चे माल का वितरण

यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि कई कृषिक कच्चे मालों के सम्बन्ध में उनकी उपलब्धि का प्रश्न साधारण महत्व का है। कपास की जीनिंग करनेवाली मिलों, सूती मिलों, चीनी मिलों, तेल मिलों तथा चटकलों की मौजूदगी से यहीं देखने में आता है कि उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग में पूर्ति के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में माल की पूर्ति भरपूर है, बल्कि यह है कि जिस किसी खास क्षेत्र में हम लघु उद्योगों को विकसित करना चाहते हैं, वहाँ पर्याप्त है या नहीं। अगर पर्याप्त है भी तो प्रश्न यह उठेगा कि वे उन्नत प्रौद्योगिकीवाले बड़े यंत्रों की पूर्ति के लिए जायेंगे या कम उन्नत प्रौद्योगिकीवाले छोटे यंत्रों की। दूसरे शब्दों में, कच्चे मालों के वितरण की व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि कम उन्नत प्रौद्योगिकीवाले लघु उद्योग अपनी भूमिका अदा करने में समर्थ हो सकें। तब प्रश्न यह उठेगा कि जब उन्नत प्रौद्योगिकी से माल तैयार कर सकते हैं तो कम उन्नत या मध्यम प्रौद्योगिकी का क्यों पक्षपात पूर्ण बढावा दिया जाय।

तब हमें सामाजिक आयोजन और नीति के मूल में जाना पड़ेगा। ऐसे समाज में, जिसका नियमन औपचारिक योजनानुसार नहीं है, यह प्रौद्योगिकी अपनायी जाय या वह, स्वभावतया आर्थिक लागत के आधार पर सोची जा सकती है। जो प्रौद्योगिकी अधिक दक्ष और

स्वीकार्य हो वह गृहेगी और दूसरी किनारे हो जायेगी। उससे बेकारी, स्थानान्तरण, तकलीफें आदि जैसी सामाजिक समस्याएँ आ सकती हैं और स्वयम् आर्थिक प्रगति या राज्य के समाज कल्याण कार्यों के जग्ये उनकी सुविधा ली जा सकती है। किन्तु कुछ दूर तक यह भी हो सकता है कि उनकी कोई खबर न ली जाय और समस्याएँ बढ़ती जाय। मुनियोजित समाज में इन मारी स्थितियों का अन्दाज लगा लेना होता है और यथा सम्भव उनकी व्यवस्था करनी होती है। और, इस प्रकार व्याख्या में हम ऐसे स्थल पर पहुँचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी का चयन प्रौद्योगिकी के कुल सामाजिक मूल्यांश पर निर्भर करेगा। इसके लिए एक मापदण्ड तैयार करना पड़ेगा— एक ऐसा मिश्रित सूचकांक, जिसके तैयार करने में आर्थिक और सामाजिक तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष, समस्त मूल्यों पर विचार करना होगा।

इस संदर्भ में मैं अपनी उस प्रारम्भिक जाँच का उल्लेख करना चाहूँगा, जो कुछ साल पहले वस्त्रोद्योग में विभिन्न किस्म की प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में मेने की थी। उत्पादन की ये पाँच श्रेणियाँ उस जाँच में शामिल थीं (१) कटाई तथा बुनाई या मिश्रित मिलों में बननेवाला कपड़ा, (२) मिल सूत से शक्ति चालित करघों पर बना कपड़ा, (३) मिल कने सूत से हाथ करघे पर उत्पादित कपड़ा, (४) अम्बर के सूत से उत्पादित खादी, तथा (५) पारम्परिक चरखे के सूत से उत्पादित खादी। साधारण लागत जैसे कच्चा माल, मजदूरी तथा अन्य उत्पादन व्यय और उपशीर्षों के अतिरिक्त सामाजिक लागत के तत्व भी शामिल करके तुलनात्मक दृष्टि में उसे पूर्ण और सर्व सम्पन्न बनाने की कोशिश की गयी। सामाजिक लागत के जो महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किये गये वे हैं विस्थापित और बेकार कर्मचारियों को बेकारी की सहायता की लागत और गहरी जमाव की लागत। यह मापने योग्य थे या कम से कम किसी प्रकार की माप ईजाद की जा सकी। अन्य तत्व, जैसे कि बंधे में या भौगोलिक स्थानान्तरण, बड़े नगरों में रहने तथा काम करनेवालों पर शैक्षणिक प्रभाव, अपने घर में तथा गाँव में काम करनेवालों का मनोवैज्ञानिक सतोंप आदि, जिनके माप नहीं किये जा सकते, छोड़ दिये गये। ये सारे आकड़े एक वक्रव्य के साथ प्रकाशित किये गये, जिसका एक स्वरूप नीचे उद्धृत है

लागत समुक्त मिल सूत मे मिल सूत से अम्यग परम्परा-
मड मिल शक्ति करवा राख करवा गादी गन
उनाई उनाई गादी

कच्चा माल

मजदूरी

क कतार

म बुनाई

वितरण व्यय

सहित उपशीर्ष

बेरोजगारी

राहत खर्च

गहरी जमाव व्यय

प्रति गज ढपडे पर कुल व्यय

इस सम्बन्ध के आकड़ों (या उसके उपसहार) को यहाँ देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे काफी पुराने हो गये हैं। किन्तु उक्त तरीके को उतार करने में खाम बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए सही और समुचित प्रौद्योगिकी का निर्धारण करने के लिए जाँच का वह तरीका विचारणीय है।

समुचित प्रौद्योगिकी

मध्यम प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जब तक उनकी सुरक्षा के रास्ते नहीं निकाल लिये जाते, इस बात का खतरा है कि मध्यम प्रौद्योगिकी को सत्य की तरह कल्पना मात्र समझा जायेगा और तब कोई व्यंग्य से यह भी पूछेगा कि 'मध्यम प्रौद्योगिकी कौन सी बला है।' और, उत्तर की बिना प्रतीक्षा किये चलता जायेगा। कुछ रूपों में 'उपयुक्त प्रौद्योगिकी' और 'अनुकूलतम प्रौद्योगिकी' बेहतर प्रतीत होगी, क्योंकि शब्दार्थों के अनुकूल उनका प्रयोजन है विकास के किसी खास क्रम या अवस्था से और उनकी उस स्थिति में किसी तरह की घटती-बढ़ती नहीं हो सकती। यह भी बात है कि उनका आधार किसी ऐसी अव्यक्त धारणा पर नहीं है कि समस्त ग्रामीण क्षेत्रों तथा उद्योगों के लिए मध्यम प्रौद्योगिकी ही, सही प्रौद्योगिकी होगी। क्षेत्र या उद्योग तथा स्थितियों में यथानुकूल कोई भी प्रौद्योगिकी—उन्नत, मध्यम या निम्न—समुचित हो सकती है।

अन्ततः इस सम्बोध के व्यावहारिक उपयोग पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है—इसे मध्यम प्रौद्योगिकी कहिये या कोई भी दूसरा उपयुक्त नाम दीजिये। व्यावहारिक उपयोग के लिए अगर सम्बोध को ठोस

रूप नहीं दिया गया तो यह प्रौद्योगिकी, आयोजकों तथा नीति-निर्धारकों के दगावों में ही पड़ी रह जायेगी और प्रशासक इसको गौण कर देंगे। उनके लिए एक छोटा विश्लेषण और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है, जो कुछ ऐसे लघु उद्योगों के लिए विस्तृत विवरण तैयार करे, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि की सम्भावना हो। इस विश्लेषण और अनुसंधान कार्य के परिणाम सिर्फ योजना बनानेवाले या नीति निर्धारित करनेवाले संस्थानों को ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवम् छोटे निजी उद्योगपतियों को भी एक प्रौद्योगिकी सूचना एव विस्तार सेवा केन्द्र के जरिये दिये जायें। उक्त दोनों केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग कार्यक्रम के आयोजन तथा कार्यान्वयन में लगे प्रतिष्ठानों के निकट सम्पर्क में काम करना होगा।

विचारणीय तथ्य

- १ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी के निर्धारण में जिन विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करना है, उनमें एक है पूँजी स्रोत व कच्चे माल की प्राप्ति।
- २ ग्रामोद्योग तथा कृषि व पशुपालन की प्रौद्योगिकी में कुछ किस्म की समानता व परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये।
- ३ अगर अधिक तथा कम उन्नत प्रौद्योगिकियों को किन्हीं सामाजिक कारणों से देहातो में साथ-साथ चलाना है तो कच्चे मालों के वितरण की योजना आवश्यक है।
- ४ प्रौद्योगिकी तथा प्राविधिक परिवर्तन की गति के प्रश्नों पर सम्पूर्ण सामाजिक माप के रूप में विचार करना तथा उनका निर्णय करना चाहिये।
- ५ प्रौद्योगिकी की सम्बद्धता के माप हेतु एक मिश्रित सामाजिक माप सूचकांक तैयार करना चाहिये।
- ६ मध्यम प्रौद्योगिकी कोई अच्छा या उपयुक्त पर्याय नहीं है। उसकी जगह 'सही' 'समुचित' या 'अनुकूल' प्रौद्योगिकी सोचा जा सकता है।
७. 'समुचित प्रौद्योगिकी' को एक ठोस रूप दिया जाय, उसे माप के योग्य बनाया जाय तथा ऐसा सविन्यास किया जाय कि व्यावहारिक उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए विश्लेषण और अन्वेषण केन्द्र तथा प्रौद्योगिक सूचना और विस्तार सेवा केन्द्र की आवश्यकता पड़ेगी। ●

ग्रामीण औद्योगिकीकरण

पुतुपरम्बिल म. मथाई

ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने से राज्य का उतना ही तात्त्विक होना चाहिए जितना कि कृषि-उत्पादन बढ़ाने से है। ग्रामीण औद्योगिकीकरण के सुसंयोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए कच्ची सामग्री सुरक्षित रखने, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने, सामाजिक बन्धों की व्यवस्था, उत्पादन क्षेत्रों का निर्धारण आदि के सम्बन्ध में नीति-विषयक निर्णय लेने की आवश्यकता है। औद्योगिक लाइसेंस नीति तथा अनुषंगी औद्योगिक विकास को भी उद्योगों के फैलाव एवं विकेन्द्रीकरण की ओर मोड़ना होगा।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में मौजूदा ग्रामीण उद्योगों को बेहतरीन संगठन, वित्त की पूर्ति, अनुसंधान और प्रशिक्षण के जरिये ठोस बनाने की कल्पना की गयी थी। द्वितीय ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग (द्वितीय पंच वर्षीय योजना) समिति ने औद्योगिक विकास के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों पर जोर दिया था। समिति ने महसूस किया कि ग्रामीण उद्योगों का प्रगतिशील विस्तार और आधुनिकीकरण का सबसे कम खर्चीला लेकिन लाभदायक मार्ग है आवश्यक सेवाओं के साथ छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार करना। उसने सिफारिश की थी कि रफ़ता-रफ़ता करके जो औद्योगिक स्वरूप सामने आये, वह ऐसा होना चाहिये कि उसमें ऐसे ग्राम समूह हों जिनके अपने सहज औद्योगिक तथा शहरी केन्द्र हों। ये छोटे-छोटे शहरी केन्द्र बड़े शहरों से सम्बद्ध होंगे। इस प्रकार प्रगतिशील ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर आधारित विस्तृत नींववाला उद्योग स्तूप (पिरामिड) सामने आयेगा। उसने आगे जोर देकर कहा कि कृषि से उद्योग की ओर जाने में कौशल विकास, उत्पादन क्षेत्रों के आरक्षण, ग्रामीणों द्वारा तथा उनके जरिये संगठन खड़ा करना और बड़े पैमाने पर प्राविधिक बेकारी से बचना आवश्यक होगा।

उद्योग विस्तार

इस विचार को २६ सामुदायिक विकास औद्योगिक मार्गदर्शी परियोजनाओं का अध्ययन करनेवाले अध्ययन

दल (मिश्र दल) ने और भी निश्चित स्वरूप प्रदान किया। दल ने प्रस्ताव किया कि एक-एक विकास खण्ड में एक-एक ऐसे चुनिन्दा केन्द्र का विकास किया जाय जो अपने इर्द-गिर्द के गाँवों की आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। चुनिन्दा केन्द्र वे हो सकते हैं जो पिछले चन्द वर्षों के दौरान ऐसे प्राकृतिक अथवा महत्वपूर्ण केन्द्र बन गये हैं, जहाँ व्यावसायिक व औद्योगिक गतिविधियाँ विकसित होने लगी हैं तथा उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली हैं या फिर जमा रही हैं। ये केन्द्र, जिन्हें दल ने ग्रामीण उद्योग केन्द्र कहा है, स्थानांतरण की चौकी का काम करेंगे और स्थानीय औद्योगिक समूहों के लिए अवसर प्रदान करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य था यथा सम्भव बड़े-बड़े नगरों व शहरों के और अधिक विस्तार को कम करना तथा ग्रामीणों को यथा संभव उनके घरों के आस-पास ही रोजगारी के अवसर मुहैया करना। दल ने यह भी सिफारिश की कि इन चुनिन्दा ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों में ग्रामीण उद्योगपुरियाँ, सामान्य सुविधा केन्द्र और कारीगर प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा सकते हैं।

तृतीय पंच वर्षीय योजना में देश भर में, विकेन्द्रित आधार पर रोजगारी और आमदनी के साधन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में लघु उद्योगों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा गया था कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में इस बात पर जोर दिया जायेगा कि गाँवों तथा छोटे-छोटे कस्बों व ऐसे अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों के और अधिक

विकास को प्रोत्साहन मिले, जिनमें निश्चित औद्योगिक क्षमता है। इस सम्बन्ध में सबसे पहला कदम होगा उन क्षेत्रों की जानकारी करना जहाँ विजली, कच्ची कृषिक सामग्री की भरपूर पूर्ति, यातायात के उन्नत साधन आदि जैसी विभिन्न बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त हैं अथवा होनेवाली हैं।

बड़े गाँव : केन्द्र बिन्दु

इस विचार का अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शी आयोजन दल ने भी समर्थन किया है कि ग्रामीण औद्योगीकरण और उद्योगों के विस्फुरण के लिए बड़े गाँव तथा छोटे कस्बे केन्द्र बिन्दु होने चाहिये। दल ने इस बात पर जोर दिया कि गाँवों में औद्योगिक उत्पादन तथा सेवाओं को अर्थ-शास्त्र की शब्दावली में बाह्य किफायती-लागत कम करनेवाले प्राप्त लाभ अर्थात् सुविधाएँ, जो तैयारमालकी बिक्री तथा पूर्ति आदि के लिए सुविकसित बाजारवाले स्थानों में आर्थिक गतिविधियाँ चलाने के फलस्वरूप मिल जाती हैं—के अभाव के कारण बुरी तरह घाटे में रहना पड़ेगा। इसके दूसरी ओर दल ने यह भी महसूस किया कि देश के भिन्न-भिन्न भागों का सतुलित विकास, आर्थिक प्रगति के लाभ अल्प-विकसित क्षेत्रों तक पहुँचाना और उद्योगों का विस्तृत विस्फुरण अथवा फैलाव आयोजित विकास के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहले से ही अत्यधिक भीड़भाड़वाले घने बसे बड़े-बड़े शहरों में—जहाँ बहुत ही जटिल आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याएँ खड़ी हो गयी हैं—उद्योगों के जमा हो जाने से बचने के लिए दल ने महसूस किया कि कोई न कोई ऐसा मध्यम मार्ग होना ही चाहिए, जोकि शक्ति और परिवहन जैसी औद्योगिक सुविधाओं की लागत नीची रख सके, शहरी व्यवसायों से सम्बद्ध अर्थात् जुड़ी हुई बाह्य किफायते प्रदान कर सके और यह सब करते हुए भी बहुत कुछ उद्योग तथा उनसे सम्बद्ध अन्य सेवाएँ फिलहाल गाँवों में जो लोग रहते हैं उनमें से अधिकांश के समीप ला सके। दल ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि मध्यम आकार-प्रकार के उद्योगों को जानबूझ कर शहरों में

प्रोत्साहित करने तथा गाँव और कस्बे के बीच उत्पादन महानुबन्ध को बढ़ाने में यह काम किया जा सकता है। हाल ही में एक सम्मेलन के लिए प्रसारित अपने एक निबन्ध में डाक्टर धनजय राव गाडगिल ने भी चुनिन्दा 'विकास केन्द्रों' का विकास करने का सुझाव दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की प्रगति का मूल्यांकन करने, नीति और आयोजन सम्बन्धी समस्याओं में सलाह देने तथा ग्राम्य क्षेत्रों में ग्राम और लघु स्तरीय उद्योगों का सघन विकास करने के लिए कार्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग ने एक उच्च स्तरीय ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति नियुक्त की है। देहाती क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का सघन और सुसंयोजित विकास करने के लिए उक्त समिति ने एक योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत ४५ परियोजनाएँ शुरू करने की व्यवस्था है।

सर्वांगीण विकास का अंग

सन् १९५६ में प्रारम्भ की गयी २६ सामुदायिक विकास औद्योगिक मार्गदर्शी परियोजनाओं के अनुभव से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मात्र निधि-संग्रहण या विभिन्न माध्यमों के समन्वित प्रयासों अथवा पहले से ही चल रही समान प्रकार की योजनाओं का सम्भवतः अधिक सघन विस्तार करने से ही ग्रामीण औद्योगीकरण पूर्ण नहीं हो जायेगा। पैतालीस ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के सर्वेक्षण प्रतिवेदनो से भी उक्त कथन की भलीभाँति सम्पुष्टि हो चुकी है। उक्त प्रकार के कदम उठाने से निश्चय ही धन-राशि के कुशल उपयोग और कार्यक्रम के सक्षम कार्यान्वयन को प्रश्रय मिलेगा, लेकिन इससे ग्रामीण औद्योगीकरण के प्रधान उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी अर्थात् ग्राम्य क्षेत्रों में उद्योगों का फैलाव तथा विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकेगा। सच्चाई यह है कि देश के औद्योगीकरण के समग्र स्वरूप के अभिन्न अंग-स्वरूप एक निश्चित सम्बोध के रूप में ग्रामीण औद्योगीकरण का विकास होना अभी बाकी है। ग्रामीण औद्योगीकरण

पर उसे अलग-थलग रख कर विचार नहीं किया जा सकता। वह क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का अंग होता चाहिये—मौजूदा साधन-स्रोतों के आधार पर ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों के सघन विकास के आधार पर। इसमें प्राविधिक विकास विभाग, औद्योगिक लाइसेंस समिति, कच्चे माल का बँटवारा करनेवाला अभिकरण और आयात लाइसेंस विभाग, परिवहन का आयोजन करनेवाले अभिकरण तथा आर्थिक और सामाजिक बन्ने खर्चों व अनुसंधान-सुविधाओं सम्बन्धी अभिकरणों जैसे अनेक नीति-निर्णायक अभिकरणों के काम का शामिल होना आवश्यक है। एक सुसंयोजित ढंग से ग्रामीण औद्योगीकरण का काम हाथ में लेना एक इतना बड़ा भारी काम है, जोकि किसी एक ही विभाग अथवा मंत्रालय के कार्यक्षेत्र और कर्तव्य के बहुत परे है।

कृषि-औद्योगिक बस्तियों का विकास

मैं सोचता हूँ कि ग्रामीण औद्योगीकरण के एक सुसंयोजित कार्यक्रम में निम्न बातें आ सकती हैं

१ परम्परागत कारीगरों को अपने कौशल में मुधार करने, उधार, कच्चे माल व उन्नत साधन-संरजामों की पूर्ति, औद्योगिक सहकारों के संगठन और तैयार माल की बिक्री-व्यवस्था करने में मदद देने के लिए एक साधारण कार्यक्रम, जिसके कार्यक्षेत्र में समूचे देहात आ जायें।

२ जुगत और दीर्घ-कालीन कार्यक्रम के रूप में औद्योगिक विकास के लिए आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के सम्वर्द्धन स्थलों को पहचानना आवश्यक है। इन्हें 'ग्रामीण औद्योगिक विकास केन्द्र' कहा जा सकता है। इन केन्द्रों में विकास के लिए ऐसे उद्योगों का चुनाव किया जाना चाहिए, जो मुख्यतः स्थानीय कच्ची सामग्री तथा स्थानीय माँग पर आधारित हों। उदाहरणार्थ ऐसे केन्द्रों में विकास के लिए इन उद्योगों का चुनाव करना बहुत उपयुक्त होगा—प्रशोधन उद्योग, पशु-पालन और वन्य उत्पादनो पर आधारित उद्योग। कृषि उपकरणों का निर्माण, सुतार घर, भवन निर्माण

सामग्री उत्पादन, वस्त्र, जूता और खाद्य उद्योग। उपयुक्त सामाज्यार्थिक बन्ने खर्चों और संचार सुविधाओं को व्यवस्था के मामले में भी इन ग्राम्य विकास केन्द्रों को सर्वाधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिये। यह अपेक्षा की जा सकती है कि रफ़ता-रफ़ता करके इस प्रकार के केन्द्र कृषि-औद्योगिक बस्तियों के रूप में विकसित हो सकते हैं।

आधुनिक प्रविधि-मूलक उद्योग

३ स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार ग्रामीण औद्योगिक विकास केन्द्रों में मध्यम तथा दीर्घ स्तरीय उद्योगों की आवश्यकताएँ पूरी करनेवाले अनुपगी (एन्सीलरी) और पोषक (फीडर) उद्योगों व अन्य नये प्रकार के विकास को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इन उद्योगों में आधुनिक प्रविधि का प्रयोग होगा।

४ शहरों व कस्बों में विस्तारशील बाजारों तथा अपने आस-पास के गाँवों को सेवा-सुविधाएँ प्रदान कर सकने की दृष्टि से उनके पास-पड़ोस के देहाती क्षेत्रों और सामुदायिक विकास खण्डों में उद्योगों के विकास की विशेष सम्भावनाएँ हैं। कस्बों को औद्योगिक विकास के केन्द्र का रूप देने की योजना बनायी जा सकती है और वहाँ से उसके आस-पास के गाँवों में सामान्य सुविधाएँ प्रदान करते हुए उनका विस्तार किया जा सकता है। दीर्घ स्तरीय उद्योगों के लिए अनुषंगी उत्पादन पर जोर दिया जा सकता है। आस-पास के देहातों में छोटे उद्योगों की इकाइयाँ खोल कर इन बड़े उद्योगों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं। शहर में प्रशोधन और फिर वहाँ के निवासियों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए वितरण करने हेतु पास के गाँवों में दूध का उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार स्थानीय बाजार तथा निर्यात के लिए कृषि उत्पादन व अन्य कच्ची सामग्री का प्रशोधन किया जा सकता है। ऐसा करने का उद्देश्य है एक तरफ कृषि विभाग और लघु उद्योग विभाग के बीच तथा दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी अर्थ-व्यवस्था

के मध्य सुसम्बन्ध स्थापित करना, जिसमें भविष्य के लिए कृषि-औद्योगिक आधार की प्राप्ति होगी।

५ ग्रामीण कर्मी-शक्ति को किसी अंश में कृषि से हटा कर इन ग्राम्य विकास केन्द्रों में शुरू किये गये उद्योगों में प्रवृत्त करने के लिए चौकस और आयोजित प्रयास भी अवश्य किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करनी पड़ेंगी।

राज्य कार्यवाही के लिए

ग्राम्य और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना राज्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिये जितना कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का काम है। एक सुसंयोजित ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु कच्ची सामग्री सुरक्षित रखने, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पूर्ति करने, ग्राम्य औद्योगिक विकास केन्द्रों में उपयुक्त रूप से सामाजिक बंधे खर्च प्रदान करने,

चूनिन्दा उद्योगों के मामले में बड़े और छोटे उद्योगों के लिए उत्पादन-क्षेत्रों का निर्धारण करने तथा उधार-विक्री व्यवस्था सम्बन्धी उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में भी अनेक महत्वपूर्ण नीति-विषयक निर्णय लेने पड़ेंगे। औद्योगिक लाइसेंस नीति और अनुपगी औद्योगिक विकास को भी उद्योगों के विकेन्द्रीकरण तथा विस्फुरण के उद्देश्य की ओर उन्मुख करना होगा।

अन्त में यह जानकर खुशी होगी कि ग्रामीण औद्योगीकरण के विषय पर फिलहाल उच्चतम शिखर पर गहरा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए श्री जयप्रकाश नारायण तथा प्रोफेसर धनंजय राव गाडगिल खासतौर से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण पक्ष पर सरकार एवं जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयत्न किये हैं।

नयी दिल्ली १८ फरवरी १९९४

संगठित उद्योगों में सूती वस्त्रोद्योग, वनस्पति तेल, रसायन, दियासलाई, सीमेंट और धातु निर्माण महत्वपूर्ण हैं। सूती वस्त्रोद्योग अधिकतर अहमदाबाद नगर में ही केन्द्रित है। सन् १९५५-५६ में इसमें २,१६,००० लोग काम पर लगे थे और उन्होंने कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग आधा उत्पादित किया। रसायन उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं द्वारका, भावनगर, बड़ौदा, बलसार तथा कच्छ। इजीनियरिंग उद्योग का अधिकांश काम अहमदाबाद, भावनगर, बड़ौदा, सूरत और राजकोट में ही होता है।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात : नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाईड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा*

लालभाई र. देसाई

बुनियादी शिक्षा बाल-केन्द्रित, समाज-केन्द्रित, वातावरण-केन्द्रित और दस्तकारी-केन्द्रित है। अब तक बुनियादी शिक्षा केन्द्रों में जिन दस्तकारियों का समावेश किया गया है वे कतार्ई और बुनाई, बर्छगीरी अथवा कृषि तक ही सीमित है। इनमें भी प्रायः कतार्ई और बुनाई पर ही जोर दिया जाता रहा है। अब वह समय है कि हम अन्य दस्तकारियों के सम्बन्ध में भी मोचें। इस धारणा को दूर करने के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिये कि बुनियादी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है।

प्रारम्भ में जो योजना वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध थी १९३९ में उसका नाम बुनियादी शिक्षा पड़ा और अब वह हिन्दुस्तानी तालिमी सघ के अनुसार नयी तालीम के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। तिस पर भी, देश के किसी भी राज्य में उसका पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो सका है। यह एक तथ्य है कि जहाँ कहीं यह योजना शुरू की गयी है, उसकी कोई विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। क्या इसमें कोई अन्दरूनी कमी है? क्या यह योजना असफल हुई है? क्या इसका कार्यान्वयन, जैसा कि डाक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है—जोकि गांधीजी के बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी विचार को स्वरूप प्रदान करनेवाले एक अग्रगण्य शिक्षाशास्त्री थे—एक धोखा है? मैं इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा।

मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि योजना में कोई अन्तर्निहित कमी नहीं है। जैसा कि मैंने अन्यत्र एक अन्य सन्दर्भ में—शिक्षा मंत्रालय द्वारा इन्स्पेक्शन ऑफ बैसिक स्कूल्स (बुनियादी विद्यालयों का निरीक्षण) विषय पर प्रकाशित 'मोनोग्राम' में—बताया है, यह चार ठोस स्तम्भों पर आधारित है (१) बुनियादी शिक्षा बाल-केन्द्रित है और इसलिए विकासशील, (२) बुनि-

यादी शिक्षा समाज-केन्द्रित है, (३) बुनियादी शिक्षा वातावरण-केन्द्रित है, और (४) बुनियादी शिक्षा दस्तकारी-केन्द्रित है।

बालक : प्रथम स्तम्भ

बालक में प्रतिक्षण विकास होता है। उसका स्वभाव बदलता है और योग्यताएँ बढ़ती हैं। एक कक्षा में सभी बालक समान प्रगति नहीं करते, उनके विकास की गति और तरीका समान नहीं होता। अतएव शिक्षक को ऐसे तरीके अस्तित्व में करने पड़ते हैं जो अलग-अलग बच्चों के अनुकूल हों। उसे अलग-अलग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करना होता है। अतएव तौर-तरीकों और सामग्री में परिवर्तन होता रहता है। आज जिस बच्चे के लिए जो चीज अच्छी ओर पर्याप्त है कल अथवा दूसरी प्रकार के बच्चे के साथ हो सकता है वह वैसी ही न हो, और नहीं होगी। यदि शिक्षक पहले इस्तेमाल किये गये तरीके ही अपनाये तो इससे निश्चय ही शैक्षणिक रुढ़िवाद और लकीर के फकीरवाले सिद्धान्त को प्रश्रय मिलेगा। बाल-केन्द्रित शिक्षा के लिए लचीलेपन, परिवर्तन, अनुकूलन और समझन की आवश्यकता है।

समाज : द्वितीय स्तम्भ

बुनियादी शिक्षा समाज-केन्द्रित है। इसमें न केवल बच्चे को समाज में रहने योग्य, बल्कि समाज के साथ

* दिनांक ७ और ८ मार्च १९६४ को बम्बई में सम्पन्न बुनियादी शिक्षा कार्यकर्ता सम्मेलन में दिये गये अध्यक्षीय भाषण से।

रहने लायक भी बनाने की बात आती है। प्रति पल समाज में परिवर्तन होता रहता है। इसमें उन्नति और अवनति दोनों होती है। शिक्षक को यह देखना पड़ता है कि उसके तौर-तरीको अथवा संगठन और शिक्षण में अवनति रोकने तथा उन्नति करने में योगदान मिले। समाज कभी गतिहीन नहीं हो सकता। शिक्षा के उद्देश्य समाज द्वारा निर्धारित होते हैं और समाज में होनेवाले परिवर्तनों के साथ-साथ वे भी बदलते रहते हैं। इसलिए परिवर्तनों का तकाजा है कि समजन और अनुकूलन हो तथा साथ ही साथ शिक्षा के वैसे साधन भी हो।

वातावरण तृतीय स्तम्भ

बुनियादी शिक्षा वातावरण-केन्द्रित है। इसे सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के वातावरण के अनुरूप होना पड़ता है। सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार का वातावरण ही बदलता रहता है। एक ही प्रकार का भौतिक वातावरण यद्यपि स्थिर दिखायी पड़ता है, पर भिन्न बालको के लिए भिन्न पृष्ठभूमि बन सकता है और इसलिए शिक्षक को अपने तौर-तरीको में समजन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है तथा हर मर्तबा उसे नये साधन व सामग्री तैयार करनी पड़ती है।

दस्तकारी: चतुर्थ स्तम्भ

बुनियादी शिक्षा दस्तकारी-केन्द्रित है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह गतिविधि-केन्द्रित है और, गतिविधि-केन्द्रित शिक्षा सदैव बदलती रहती है, कार्यशीलता सदैव ही एक समान नहीं रहती। एक गतिविधि किसी एक सन्दर्भ में एक बालक के लिए कुछ अर्थ रखती है, तो दूसरे के लिए उससे बिल्कुल भिन्न। एक प्रकार की गतिविधियाँ एक तरह के बालको के लिए थका देनेवाली हो सकती हैं तो दूसरी किस्म के बच्चों के लिए वे ही गतिविधियाँ आसान बन जाती हैं।

इसलिए हम यह देखेंगे कि बुनियादी शिक्षा स्थिर और अचल नहीं है—उममें स्पन्दन है, वह चल है। वह हर कदम पर बदलती, बढ़ती और विकसित होती है।

इसके लिए शिक्षक में पर्याप्त अभिक्रम, मौलिकता, साधन-सम्पन्नता, अनुकूलन और चातुर्य का होना आवश्यक है।

योजना की सफलता

इस प्रश्न का उत्तर कि “क्या यह योजना असफल हुई है?” अशत सकारात्मक है। यह सही है कि यह विशेष प्रगति नहीं कर पायी है, लेकिन असफल भी नहीं हुई है। गैर बुनियादी विद्यालयों ओर उनकी शिक्षा पद्धति पर इसके कुछ पक्षों का प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर गैर बुनियादी विद्यालयों में भी इसके सामाजिक पक्ष तथा वातावरण के पक्ष का किसी हद तक समावेश हुआ है। उत्सवों के आयोजन, सफाई कार्यक्रमों के जरिये स्कूल का समाज के साथ सम्पर्क बढ़ा है तथा वह सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनता जा रहा है। इन पक्षों को गैर बुनियादी विद्यालयों में भी अपनाया जा रहा है। और फिर, अन्य देशों में भी सामान्य शिक्षा का शुकाव उसका सामाजीकरण करने की ओर है तथा आज हम देखते हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों पर—यहाँ तक कि उच्च शिक्षा स्तर पर भी—अच्छे-खामे परिमाण में बाह्य गतिविधियाँ चलती हैं। बालक को शिक्षा का केन्द्र समझने का मिद्धान्त भी अपना लिया गया है और शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में मुझाये गये अनेक तरीके इसी पर आधारित हैं। हमारी प्रशिक्षण संस्थाएँ अब शिक्षण के इस पक्ष पर जोर दे रही हैं और अनेक प्रगतिशील स्कूल अपनी शिक्षण-पद्धति को इस मिद्धान्त के अनुसार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार बाह्य दृष्टि से गैर बुनियादी विद्यालय बुनियादी बन रहे हैं। स्वभावतः आज लोग बुनियादी तथा साधारण विद्यालयों में विशेष अन्तर नहीं देखते।

बुनियादी शिक्षा का दस्तकारी और शिक्षा देने के तरीकेवाला पक्ष सन्तोषप्रद रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में यह स्वीकार करना चाहिये कि योजना असफल रही है। बुनियादी विद्यालयों तक में जहाँ बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक हैं, अन्य

प्रकार की शिक्षा के साथ-साथ दस्तकारी की शिक्षा देना सफल नहीं रहा है और इसके कारण ढुंढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन शिक्षकों ने कभी दस्तकारी की शिक्षा नहीं ली, केवल दो वर्ष के प्रशिक्षण से वे उसमें निपुणता हासिल नहीं कर सकते और इसलिए दस्तकारी में छात्रों की प्रगति सन्तोषप्रद नहीं है। यही मुख्य बाधा रही है और, मेरे विचार से तो सर्वाधिक गम्भीर।

सहकारी आधार पर दस्तकारी

तथापि, दस्तकारी के सामाजिक दृष्टि से उपयोगी पहलू ने मुझे सर्वाधिक आकर्षित किया है। हमारे बालकों की शिक्षा में यह एक मौलिक तत्व है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ विस्तृत प्रकाश डालना चाहूँगा।

अ सर्व प्रथम हम बच्चों के प्रारम्भिक जीवन काल में उनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है, उसका परीक्षण करें। उनके साथ हमारा जो व्यवहार होता है वह बहुत ही कमीना है और इस प्रकार उनमें एक बहुत ही हीन भावना निर्मित कर देगा। सामाजिक दृष्टि से उपयोगी दस्तकारियोंवाला पक्ष, बच्चों में दैनिक जीवन में काम आनेवाली वस्तुओं का उत्पादन करने की योग्यता के सम्बन्ध में आत्म-विश्वास भरेगा और जीवन के प्रति अपना रख निर्मित करने में सहायक होगा। मैं बच्चों की शिक्षा में इसे एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व समझता हूँ और यदि शिक्षा से बच्चों का चरित्र तथा सामान्य दृष्टिकोण निर्मित न हो तो उससे फायदा ही क्या?

आ इस योजना के जिस एक दूसरे पक्ष ने मुझे आकर्षित किया है वह है बच्चों में सहकारी ढंग से काम करने की दृष्टि के निर्माण की सम्भाव्यता। उपयुक्त रूप से दस्तकारी शिक्षा देने के लिए सहकारी आधार पर आयोजन करने की आवश्यकता होती है। दस्तकारी के सम्बन्ध में मात्र लक्ष्यक निर्धारित कर देना पर्याप्त नहीं है। इस काम की योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है और यह काम उपयुक्त रूप में नहीं होता है। आयोजन की आदत के जरिये ही

बच्चों में चन्द सामाजिक आदतों व दृष्टिकोण का निर्माण तथा विकास होता है। इस पक्ष पर सन्तोषप्रद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जैसा दस्तकारी कार्य होता है, वह व्यक्तिगत आधार पर होता है, अतएव व्यक्तिगत लाभ और सर्कीर्ण विचारवाला तत्व अब भी जारी है। सहकारी सेवा, त्याग और दूसरों के लिए काम करने की भावना पर आधारित गांधीजी की आदर्श समाज-रचना की प्राप्ति नहीं हो रही है तथा हमें आयोजन के इस पक्ष पर जोर देना पड़ेगा। इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

इ दस्तकारी की शैक्षणिक सम्भाव्यता दूसरा तत्त्व है। वास्तव में शिक्षा को दस्तकारी, समाज और वातावरण पर आधारित करना बहुत ही मुश्किल है। परस्पर सम्बद्ध शिक्षण के लिए यदि शिक्षकों को उन्हीं के साधन-स्रोतों के भरोसे छोड़ना हो तो बहुत ही योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। इस प्रकार के शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में हमें बड़ी गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा कि इस समस्या को कैसे हल किया जाय। विस्तृत सुझाव प्राप्त करके परस्पर सम्बद्ध शिक्षा को हम आसन बना सकते हैं। हममें से कुछ को एक साथ बैठ कर, जितनी दस्तकारियों का समावेश हम करना चाहते हैं उन पर मोचना पड़ेगा और उन्हें लेकर परस्पर सम्बद्ध विषयों की शिक्षा की योजना बनानी पड़ेगी। शिक्षा प्राप्त करने में अभिप्रेरण एक शक्तिशाली तत्व होता है और सम्भवतः विस्तृत तथा व्यापक सुझावों एवम् अन्य बातों से विद्यार्थियों में काम करनेवाले शिक्षकों को इससे सहायता मिल सकती है।

योजना का कार्यान्वय

तीसरा प्रश्न है क्या बुनियादी शिक्षा योजना एक धोखा है? शायद कुछ क्षेत्रों में ऐसा है। इस सम्बन्ध में प्रशासकों की ओर से निष्ठा का अभाव होना एक मुख्य कारण है। पुराने वातावरण में पले हुए तो वे हैं ही, और आज भी वे किताबी तालीम की चकाचौंध में गहरे डूबे हुए हैं, इसलिए दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा देने

मे उनकी निष्ठा नहीं है। यद्यपि सभी लोग अभिप्रेरण को शिक्षा का आधार स्वीकार करते हैं, तथापि, वे यह महसूस नहीं करते कि प्रक्रिया धीमी है तथा इस बारे में बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। चिंतन से जानो-पार्जन की गति धीमी होती है, पर साथ ही निश्चित थी। लेकिन हम जल्दी फल-प्राप्ति के आदि हैं, इसलिए हम स्मृति—अर्थात् दूसरे शब्दों में रटन्त—पर आधारित तरीके से छुटकारा नहीं पा सकते। ओर फिर, इन दिनों जीवन की प्रायः प्रत्येक दिशा में सामान्य उदासीनता का पाया जाना भी इस क्षेत्र में इस अवस्था के लिए बहुत-कुछ जिम्मेदार है। स्कूलों, सामग्री, आदि का सगठन आगे मन से किया जाता है और इसलिए डाक्टर जाकिर हुसैन जैसे व्यक्ति यत्र-तत्र जो कुछ देखने में आता है उस पर विगड उठे तथा जिस प्रकार उन्होंने अपनी खोज एवम् असन्तोष प्रकट किया उस रूप में अपने को व्यक्त करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आते हैं अर्थात् जिनका शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक है, वे सभी इस योजना को नीति अथवा सिद्धान्त के रूप में स्वीकार न कर ले तब तक इस प्रकार का असन्तोष पाया ही जानेवाला है। सम्भवतः उच्चाधिकारी अधिक निगरानी रखे और आग्रह करे, तो मामला ठीक रास्ते पर आ सकता है।

दस्तकारी का चयन

अब मैं कुछ समस्याएँ सामने रखना चाहूँगा। पिछले २५ वर्ष के दौरान कताई और बुनाई अथवा कृषि या बढईगरी के अलावा अन्य किसी दस्तकारी के बारे में नहीं सोचा गया है। इन में से भी अधिकांश विद्यालयों में केवल कताई और बुनाई का ही समावेश हुआ है। इस प्रकार एक ऐसी धारणा पैदा हो गयी है कि बुनियादी शिक्षा कताई-बुनाई तक ही सीमित है। मेरी समझ में अब समय है कि हम दूसरी दस्तकारियों की भी सोचे ताकि यह जो धारणा पैदा हो गयी है और जिसका कुछ शैक्षणिक विचारक प्रतिरोध कर रहे हैं, वह दूर की जा सके कि बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध किसी एक खास

राजनैतिक दल से है। यहाँ तक कि विभिन्न कारणों से कृषि और बढईगरी के काम का भी पर्याप्त समावेश नहीं हुआ है। यही समय है कि अब हम अन्य दस्तकारियों के सम्बन्ध में भी कोशिश करें ताकि दस्तकारी-केन्द्रित शिक्षा को अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में यह खास ध्यान रखना चाहिये कि दस्तकारी सामाजिक दृष्टिकोण से लाभदायक हो और शैक्षणिक दृष्टि से जिनकी सम्भाव्यताएँ हो।

उपयुक्त साधन आवश्यक

एक धारणा यह भी है कि बुनियादी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जबकि गैर बुनियादी शिक्षा—जिसने अपनी पद्धति बदली नहीं है—शहरी क्षेत्रों के लिए है और उससे अच्छा काम-नौकरी—मिल सकेगा। शिक्षा का जो स्वरूप है और जिस प्रकार की अन्य गतिविधियों के कार्यक्रम चलाये जाते हैं, मुख्यतः वे ही उक्त धारणा के लिए जिम्मेदार हैं। हमें एक ऐसे कार्यक्रम की बात सोचनी चाहिये, जिससे उक्त धारणा मिटायी जा सके। जब तक यह धारणा है तब तक बुनियादी शिक्षा कोई विशेष प्रगति नहीं कर सकती और वांछित लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकती।

इन तीन दस्तकारियों पर भी हमने पूरा ध्यान नहीं दिया है। हम बच्चों के लिए उपयुक्त उपकरण तथा सामग्री नहीं बना पाये हैं, जिसका परिणाम यह निकला है कि दस्तकारी उत्पादन को बित्री योग्य तथा वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं की जा सकी है। जिन अन्य दस्तकारियों की बात हम सोच सकते हैं उनके साथ-साथ इन दस्तकारियों पर भी प्रयोग करने का काम किसी अभिकरण को अपने हाथ में लेना चाहिये।

उपकरणों की पूर्ति, भूमि-प्राप्ति आदि के सगठन हेतु कार्यक्षम अभिकरण स्थापित नहीं हुआ है। परिणाम यह निकलता है कि अधिकांश शक्ति और पैसा बर्बाद

जाता है। कोई ऐसा सगठन खड़ा करना आवश्यक है, जो इन सब बातों को ठीक कर सके।

बुनियादी शिक्षा योजना के जरिये जिस प्रकार के समाज का विकास करना है उसके तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद समाज की जिस प्रकार की अर्थ-रचना का विकास किया जा रहा है तथा हुआ है उसके बीच काफी अन्तर है। जब तक इन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक बुनियादी शिक्षा लोकप्रिय बननेवाली नहीं है। उदाहरणार्थ देश का औद्योगीकरण किया जा रहा है और उस हद तक गाँवों में भी लघु उद्योगों की स्थापना की जा रही है। तब क्या फिर हमें बुनियादी विद्यालयों में छोटे-छोटे कुटीरोद्योगों की शिक्षा देने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे औद्योगीकरण में सहायता मिले तथा सुविधा हो? यदि हाँ, तो उस अवस्था में हमें अपने बुनियादी विद्यालयों में समावेशनार्थ ऐसे लघु उद्योगों अथवा दस्तकारियों के बारे में सोचना चाहिये।

वैज्ञानिक जाँच की आवश्यकता

बुनियादी शिक्षा के समर्थक शिक्षाशास्त्रियों का दावा है कि बुनियादी विद्यालयों में शिक्षा-प्राप्ति विद्यार्थी बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक योग्य होते हैं। बाल-व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करने के लिए जाँच की जानी चाहिए, ताकि उक्त दावे को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया जा सके। बच्चों में किस हद तक विकास अथवा ह्रास होता है, उसकी जाँच की जानी चाहिये। सम्बन्ध में कुछ प्रयास किये गये हैं, लेकिन वे परिपूर्णतः निष्कर्षात्मक नहीं हैं। सहकारी कार्य का आयोजन करने, समाज, सामान्य जीवन अथवा राष्ट्र के जीवन में दिन-प्रति-दिन घटनेवाली घटनाओं आदि के प्रति दृष्टिकोण जैसे मामलों में बाल-योग्यता के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए कोई न कोई तंत्र खड़ा करना होगा।

बुनियादी शिक्षा के प्रति कुछ वर्गों में किस हद तक ईर्ष्या पायी जाती है तथा उसका कहाँ तक औचित्य है, इस सम्बन्ध में भी जाँच करना आवश्यक है। इन व्यक्तियों का विश्वास है कि बुनियादी शिक्षा बेकार है। इस प्रकार की मान्यता की जाँच की जानी चाहिये। इस प्रकार की ईर्ष्याओं को दूर किनार रख देने या उन पर कोई ध्यान न देने अर्थात् उनकी कोई परवाह न करने से बुनियादी शिक्षा की प्रगति में सहायता नहीं मिलती।

योग्य शिक्षकों की प्राप्ति की समस्या

शिक्षकों के दृष्टिकोण का नव सस्करण करना और उपयुक्त शिक्षकों की प्राप्ति एक महान समस्या है। नव सस्करण के सम्बन्ध में हमारे प्रयास असफल रहे हैं और सामान्य शिक्षा के व्यापक विस्तार के कारण उपयुक्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तब फिर, क्या हमें बुनियादी शिक्षा का विचार त्याग देना चाहिये अथवा उसकी आवश्यकताओं में कोई संशोधन करना चाहिये? यदि आवश्यकताओं में संशोधन करना हो तो कौन सी आवश्यकताओं में करना चाहिये? या हमें पाठ्यक्रम को कम कर देना चाहिये अर्थात् पुस्तकीय पढ़ाई में कमी करके ही दृष्टिकोण के विकास पर शक्ति केन्द्रित करनी चाहिये?

हमने उत्तर-बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में पूरी तरह नहीं सोचा है—उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में तो और भी कम कि बुनियादी शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तों के साथ आवश्यक अविच्छिन्नता कायम रह सके। इस वक्त हमें यह प्रश्न हाथ में लेना चाहिये। कुछ साहसिक प्रयोग भी करने पड़ेंगे। राष्ट्रव्यापी आधार पर कुछ जाँच-पड़ताल करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले सभी अभिकरणों को अपने काम में सहकार तथा संयोजन और समन्वय लाना होगा।

खादी उद्योग में वैज्ञानिक दृष्टि

शंकरलाल बैकर

योजना आयोग ने हाल ही में श्री बी गमकृष्ण राव की अध्यक्षता में खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है। यह दल देश भर में घूम-घूम कर तत्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर रहा है। इसी सिलसिले में उक्त दल बहमदाबाद भी गया था। प्रख्यात अनुभवी खादी कार्यकर्ता श्री शंकरलाल बैकर ने दल के समक्ष वक्तव्य दिया था, जिनके महत्वपूर्ण अंश नीचे दिये जा रहे हैं।

खादी प्रवृत्ति हमारे देश के लिए और खास करके देहातो के गरीबों के लिए अत्यन्त महत्व की है। इसलिए खादी कार्य के संचालन में जैसे गांधीजी की दी हुई भावना जरूरी है वैसे ही बड़े उद्योगों के संचालन में दिखायी देनेवाली व्यावसायिक तथा प्राविधिक (टेक्निकल) कुशलता भी उतनी ही जरूरी है।

एक दृष्टि से देखा जाय तो खादी प्रवृत्ति, वस्त्रोद्योग का छोटा किन्तु महत्व का अंग है। बड़े मिल उद्योग की प्रगतिशील इकाइयों तथा अनुभवों का अध्ययन किया जाय तो इस प्रवृत्ति के लिए भी उपयोगी विचार व सुझाव मिल सकते हैं।

मिल उद्योग का संचालन

मेरा सम्पर्क मजदूर प्रवृत्ति के कारण पिछले चालीस वर्षों से मिल उद्योग के साथ रहा है। इन चालीस वर्षों में इस उद्योग में कई छोटे-बड़े परिवर्तन हुए और आज भी हो रहे हैं। चालीस वर्ष पहले मिल उद्योग का संचालन एक प्रकार से कहा जाय तो, मुख्यतः व्यापारी दृष्टिकोण का था। उसमें विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी (टेक्नोलोजी) के विचार का स्थान गौण था। मिल के यंत्र एवम् सूत तथा कपड़ा बनाने की प्रक्रियाओं के लिए कुछ निष्णात थे। लेकिन वे उच्च दर्जे के नहीं थे। बिलायत की मिलों के काम का अनुभव रखनेवाले कुछ अंग्रेज सूत एवम् कपड़ा विभाग में दिखायी देते थे और जहाँ जरूरत होती, वहाँ उनका परामर्श लिया जाता था।

लेकिन मिल का संचालन मिल मालिक करते थे। मिल मालिक अक्सर अपने रिश्तेदारों को मिल संचालन में जिम्मेवारी का काम देते थे, क्योंकि उन पर उनका विश्वास था। उनका हित करने की दृष्टि से भी वह काम उन्हें दिया जाता था। लेकिन उद्योग के संचालन की योग्यता का विचार—कर्मचारियों का चुनाव करने में—बहुत कम करते थे। उद्योग के संचालन में व्यापारी बुद्धि विशेष काम करती थी। रूई तथा अन्य माल-सामान सस्ते से सस्ता प्राप्त करके इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया जाता था। माल उच्च दर्जे का बने, यह देखने के बजाय उस माल में अधिक से अधिक मुनाफा रहे, यह दृष्टि मुख्य रहती थी। कारीगरों की कुशलता की ओर भी खास ध्यान नहीं दिया जाता था। कारीगरों को वेतन कम दिया जा सके तो लागत खर्च कम होगा और मुनाफा अधिक, यह दृष्टि रहती थी। फिर भी, मिलों के संचालकों में एक प्रकार की सूझ थी और उस कारण जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गयी, वैसे-वैसे कुछ परिवर्तन होते गये। उस परिवर्तन के पीछे कोई खास दृष्टि नहीं थी, लेकिन परिस्थिति के साथ चलने के लिए अनिवार्य कदम उठाये जाते थे।

योग्य कर्मचारी

धीरे-धीरे संचालन में रिश्तेदारों के बदले सुयोग्य कुशलता प्राप्त व्यक्तियों की भर्ती होने लगी। प्राविधिक (टेक्निकल) विषयों के बारे में प्राविधिक स्कूलों में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की हो और उस काम की योग्यता

जिनमें हो, वैसे व्यक्तियों की नियुक्तिया होने लगी। इसमें भी आगे चल कर प्रमात्र-पत्र, अनुभव तथा कुशलता के बारे में विचार किया जाने लगा। फलतः व्यापारिक व प्राविधिक काम-काज के संचालन के लिए अधिक योग्य एवम् कुशल कार्यपालक आने लगे, लेकिन उनका स्थान गौण ही रहा।

एक अग्रगण्य मिल मालिक के साथ इस विषयक बातचीत के सदर्थ में मैंने उनके समक्ष ऐसा विचार रखा कि जैसे उद्योग में मालिक हृदय के स्थान में होते हुए पूँजी आदि की आवश्यकता पूरी करते हैं और व्यापारी क्षेत्र सभालते हैं वैसे निष्णात लोग दिमाग के स्थान पर होने से बुद्धिपूर्वक वैज्ञानिक पद्धति से उद्योग का संचालन करे तो अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने (मिल मालिक ने) कुछ अलग ही विचार रखा। उन्होंने कहा कि दिमाग भी हम ही हैं। निष्णात हमारे हाथ और पैर के स्थान पर हैं। दस-बारह साल पहले की यह बात है, लेकिन यह बात उद्योग संचालकों के उस समय के मानस का कुछ भान कराती है।

उस स्थिति में भी अब ठीक-ठीक परिवर्तन हो रहा है और आज एक प्रगतिशील मिल की संचालन समिति में प्राविधिक को प्रमुख स्थान मिलता है, जो उद्योग के मानस में हुए परिवर्तन का प्रतीक है।

निष्क्रिय जन-शक्ति का उपयोग

ऐसा लगता है कि मिल उद्योग का यह अनुभव खादी प्रवृत्ति के लिए भी ध्यान में लेने योग्य है। खादी प्रवृत्ति के आरम्भ काल में कताई-बुनाई की जो शक्ति आम जनता में पड़ी थी, उसका उपयोग करने का प्रयत्न हुआ। मिल उद्योग के विकास के साथ-साथ कताई उद्योग की स्थिति अत्यन्त कमजोर हो जाने के बावजूद, उस जमाने में कुछ बड़े उद्योगोंवाले विभागों को छोड़ कर अन्यत्र छोटे-बड़े देहातो में कताई प्रवृत्ति ठीक-ठीक परिमाण में चलती रही। परम्परागत रूप से चली आनेवाली कला के अनुसार पूनी व सूत उत्पन्न हुआ करता था।

लेकिन उस काम के विकास के लिए खास उत्साह हो, ऐसा कुछ लगता नहीं था।

बुनाई उद्योग की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा अच्छी थी और बुनकर अपना कार्य लगन तथा कुशलता से करते थे। सभी कामों में जो कला एवम् शक्ति कारीगरों में थी उसका ही उपयोग होता था। प्रायः खादी केन्द्र के कार्यकर्ता सूतकारों से सूत कतवा कर, बुनकरों से जैसा वे बुन सकते थे वैसा बुनवा कर उस माल का निकास किया करते थे। निकास के लिए उस माल में ाहको की दृष्टि से कुछ सुधार किये जाते थे। लेकिन उन सुधारों की ओर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ध्यान दिया जाता था, ऐसा नहीं कह सकते।

खादी उद्योग में विकास

जिस प्रकार मिल उद्योग में क्रमिक सुधार हुए उसी तरह समय परिवर्तन के अनुसार लोगों की जरूरत को ध्यान में रख कर कार्यकर्ताओं द्वारा खादी की किस्मों में भी अपनाने लायक परिवर्तन होते रहे। किन्तु उसमें भी वैज्ञानिक ज्ञान या विचार का हिस्सा तुलना में कम रहा। गांधीजी की दृष्टि तो आरम्भ से ही वैज्ञानिक और प्रगतिशील थी। इसलिए धुनाई और कताई के साधनों तथा प्रक्रियाओं में सुधार का आग्रह वे रखते थे। कार्यकर्ता भी नये एवम् अधिक कार्यक्षम साधनों का उपयोग करने के लिए उत्सुक थे।

इसीलिए तो गांधीजी ने उत्तम चरखे के लिए एक लाख रुपये का इनाम जाहिर किया था और उससे पहले खुद उन्होंने प्रयोग करके यरवडा चक्र ईजाद किया तथा उसे केन्द्रों में दाखिल करने का सुझाव भी दिया। यरवडा चक्र के बारे में गांधीजी के मन में शका पैदा होने पर वे पूछते कि देहातो की बहने इस चक्र को अपना सकेंगी या नहीं। लेकिन गाँवों के लोग साइकल इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इस चक्र का उपयोग करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी इस खयाल को स्वीकार करके उन्होंने यरवडा चक्र का प्रचार करने का सुझाव दिया। वह चरखा आज देहातो में प्रचलित हो गया है। ठीक वैसा

ही धुनाई के बारे में भी हुआ। यह विकास आदरणीय तथा अभिनन्दनीय है।

यह सारा होते हुए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस प्रवृत्ति के विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टि, विचार और सशोधन आदि की दिशा में पर्याप्त प्रयास हुए हों। खादी कार्य का विकास और उन्नति इस उद्योग में प्रयुक्त साधन, प्रक्रियाएँ एवम् इस कार्य में लगे हुए सूतकार तथा बुनकरो की कार्यक्षमता और केन्द्र सचालको की बुद्धि, कला शक्ति पर आधारित है। वैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक दृष्टि से यथा शक्य चिन्तन और प्रयास करने पर ही इष्ट प्रगति हो सकती है।

मिल उद्योग में आज जो वैज्ञानिक कुशलता (टेक्निकल एफीसिएसी) की दृष्टि रखी जाती है वैसे ही दृष्टि खादी उत्पत्ति केन्द्र में रखी जा सके तो खादी का भविष्य उज्ज्वल और आशास्पद बन सकता है। इस बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है कि खादी केन्द्रों में जाकर गहरा निरीक्षण किया जाय तो उससे कई उपयोगी पहलू सामने आ सकते हैं। निरीक्षक, धुनाई, कताई व बुनाई करनेवालों से एवम् देहातो की आम जनता तथा कार्यकर्त्ताओं से मिले, उनकी बातें सुने, उनकी दिक्कतें समझे और वैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक दृष्टि से विकास की शक्यताओं के बारे में उनके साथ विचार-विनिमय करे तो उससे उपयोगी मार्गदर्शन मिल सकता है।

कार्यकर्त्ताओं की अवस्था

आज के उत्पत्ति केन्द्रों के सचालको की स्थिति भी जानने लायक है। खादी उत्पत्ति केन्द्रों के सचालको ने देश एवम् गरीब लोगों की काफी सेवा की है। वर्षों से वे अन्य मनोरथों को ताक पर रख कर ग्रामीणों की सेवा में डूबे हुए हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा ऋषियों की तपश्चर्या जैसी है। उनका काम असाधारण और काफी जिम्मेदारी का है। खादी उत्पादन के लिए छोटी-बड़ी सारी प्रक्रियाएँ उन्हें खुद देखनी पड़ती हैं। मिलों में अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग निष्णात तथा प्राविधिक होते हैं। मिल के यंत्रों पर निगरानी

रखने के लिए इन्जीनियर और उनके सहायक, 'ब्लोरूम', कार्डरूम, फ्रेम, थ्रोसल, कताई व बुनाई विभाग आदि के लिए भिन्न-भिन्न निष्णात और उनके सहायक, सुपरवाइजर और फुटकर काम करनेवाले अलग-अलग दर्जे के अधिकारी रहते हैं। मिलों में व्यापारी काम में रूई का स्टॉक खरीदनेवाले, बाजार का अध्ययन करनेवाले, माल कैसा बनाया जाय उस बारे में सलाह देनेवाले, आदि होते हैं। लेकिन खादी काम के लिए उत्पत्ति केन्द्र में दो-चार कार्यकर्त्ता ही होते हैं। उन्हें रूई से कपड़े तक का सारा काम खुद ही करना तथा देखना पड़ता है। ये सब जिम्मेदारी-पूर्ण काम करनेवालों के वेतन भी ऐसे हैं कि यदि भावना का बल न हो तो खादी काम करनेवाले आदमी प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाय।

उपकरणों में सुधार

खादी उत्पत्ति केन्द्रों की स्थिति सुधारने के काम में गहरे निरीक्षण, विचार व प्रयोगों की जरूरत है। उस ओर खास ध्यान देना जरूरी है। कार्यकर्त्ताओं के विकास के साथ-साथ धुनाई, कताई और बुनाई का काम करनेवाले कारीगरों का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन का आधार उनकी कलापूर्ण शक्ति पर निर्भर है। पुराने साधन एवम् प्रक्रियाओं के अतिरिक्त प्रयोग समिति की ओर से जो नये साधन बन रहे हैं और जिनका क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है, उन साधनों के विकास की शक्यता के बारे में भी गहरा अध्ययन व मनन करना जरूरी है। धुनाई का जो नया यंत्र ईजाद हुआ है, उससे धुनाई बहुत अच्छी होती है। कताई के लिए अम्बर का जो नया नमूना बना है उससे उत्पादन के साथ-साथ सूत के गुण-स्तर में भी सुधार हुआ है। बुनाई में लम्बे ताने की पद्धति से बुनकरो की आय में सतोषजनक वृद्धि हो सकी है।

इन सभी साधनों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण एवम् विचार की जरूरत है। अम्बर काम के बारे में असतोष व्यक्त किया जा

रहा है, लेकिन उसके कारण भी अच्छी तरह जाँच कर समझने योग्य है। अम्बर का पुराना नमूना आज के नये नमूने के समान कार्यक्षम नहीं है, फिर भी वह अच्छा काम दे सकता है। लेकिन कई स्थानों में वे चरखे अच्छे नहीं बने, जमावट अच्छी नहीं हुई, कतवारों को योग्य तालीम नहीं दी गयी, मरम्मत का समुचित प्रबंध नहीं हो सका, इन सारी त्रुटियों के बारे में सर्वेक्षण करने से उपयोगी जानकारी मिल सकती है और भविष्य में जो-जो विषय खास ध्यान देने योग्य हों उन पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सकता है।

उत्पादन व बिक्री : दोनों का महत्व

मिल उद्योग में कारीगर, छोटे-मोटे काम करनेवाले एवम् सुपरवाइजर आदि संचालकों की शक्ति के विकास के लिए 'ट्रेनिंग विदिन इण्डस्ट्री' (उद्योग में तालीम) जैसा कार्यक्रम रहता है। इसका हेतु यह है कि नियमानुसार काम चल रहा हो उसका सभी को समुचित ज्ञान, समझ और तालीम आदि देकर उनकी शक्ति में अच्छी वृद्धि की जा सके। खादी उत्पादन कार्य में इस दिशा में क्या हो सकता है, वह सोचने योग्य है।

जैसे खादी उत्पत्ति का प्रश्न महत्व का है वैसे ही उसकी खपत का प्रश्न भी। खादी उत्पत्ति के साथ-साथ उसकी बिक्री में भी काफी वृद्धि हुई है। फिर भी, उसमें

विकास के लिए काफी गुंजाइश है। देहातों और शहरों में खादी इस्तेमाल करनेवाले किस प्रकार का कपड़ा पसंद करते हैं, इस बात का अध्ययन करके माँग के अनुसार उत्पादन की व्यवस्था हो तो आज जो बिक्री होती है उससे भी अधिक हो सकने की संभावना है।

खादी काम का प्रभाव

यह बहुत खुशी की बात है कि खादी प्रवृत्ति का अध्ययन हो रहा है। यह ज़रूरी लगता है कि यह निरीक्षण यथा संभव गहराई से किया जाय और खास करके उत्पादन केन्द्रों में किया जाय। कतवार, बुनकर, कारीगर वर्ग, उत्पादन एवम् बिक्री कार्यकर्ता, इन सबकी शक्ति तथा योग्यता की जाँच तो ज़रूरी है ही, लेकिन इस कार्य के कारण गाँव के लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति पर पड़नेवाले असर की भी जाँच करना उपयोगी साबित होगा, ऐसा लगता है। गुजरात में इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिए खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने व्यवस्था की है। उस पर से जो जानकारी मिलेगी, वह बहुत ही उपयोगी हो सकेगी। इस सर्वेक्षण योजना के द्वारा अम्बर चरखा आधारित कुटुम्बों में से २४६ कुटुम्बों की स्थिति की जाँच हुई है। उसकी हकीकत का सारांश देखने योग्य है। विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के सर्वेक्षण हो तो वे बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।

अहमदाबाद ५ फरवरी १९९४

प्रति प्रौढ़ प्रति दिन १५ औंस अनाज और तीन औंस दाल का अनुमान करते हुए, वर्तमान खाद्य उपभोग-आदत के आधार पर राज्य की आवश्यकताएँ इस प्रकार होने का अनुमान लगाया जाता है : ५ लाख १० हजार टन चावल, ४ लाख टन गेहूँ; १७ लाख टन ज्वार, बाजरा आदि, और ५ लाख ३० हजार टन दाल। इन अनाजों के वार्षिक उत्पादन से पता चलता है कि प्रायः सभी मामलों में कमी है। दाल और ज्वार, बाजरा आदि तथा चावल के सम्बन्ध में यह कमी अधिक है।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात · नेशनल
कॉउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन और ग्राम इकाई

प्रमोद कुमार पटनायक

ग्राम इकाई क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का संगठन सहकारी आधार पर होना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिलहाल जो स्थापित हैं उनके कामों का उपयुक्त विभाजन होना चाहिये। ग्राम इकाई क्षेत्रों में ग्रामीणों की जरूरत की चीजों की पूर्ति के लिए उपभोक्ता भण्डारों का गठन किया जा सकता है।

भारत में उपभोक्ता सहकार के विषय पर नियुक्त अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने स्वीकार कर ली हैं। दल द्वारा की गयी अनेक सिफारिशों में से एक यह है कि तेल निस्सारण, चावल कुटाई, आटा पिसाई आदि जैसे सरल प्रशोधन कार्य उपभोक्ता सहकारी भण्डार करेंगे। दल ने यह भी कहा है कि उपभोक्ता भण्डारों का गठन ग्रहणी क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिये, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वे प्राणवान इकाइयों के रूप में नहीं पनप सकेंगे। ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के भण्डारों का गठन करने के लिए एक ही कसौटी रखी गयी है—उनकी जिव्यता। अगर किसी विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में सिफारिशों के अनुसार अनुकूलतम आकार प्राप्त कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में भी उक्त कार्यक्रम का विस्तार करने में सम्भवतः कोई आपत्ति नहीं होगी।

भिन्न अवस्थाएँ

प्रतिवेदन में ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्णतः अवहेलना नहीं कर दी गयी है। ऐसा कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता गतिविधि को स्टोर विभाग खोल कर सेवा सहकार का काम भी करना है। यह सिफारिश कि “यदि रुपये पैसे की दृष्टि से शक्य हो, तो प्राथमिक भण्डारों को साधारण प्रशोधन कार्य करना चाहिये” सहकारों पर भी—उनके साधारण कामों के साथ उपभोक्ता सम्बन्धी कार्यशीलता को शामिल करके—लागू हो सकती

है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सिफारिशें भण्डारों की स्थापना और उनके प्रशोधन कार्य को सीमित नहीं करती।

उस प्रकार की गतिविधि को शामिल करने का विचार सम्भवतः इंग्लैण्ड के उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन से लिया गया है। यहाँ तक कि इंग्लैण्ड में भी प्रारम्भिक अवस्थाओं में उत्पादक सहकारों की ओर से उपभोक्ता सहकारों द्वारा उत्पादन कार्य हाथ में लेने का कड़ा विरोध किया गया था। उक्त दो प्रकार के उत्पादन में अन्तर यह था कि उत्पादक समितियों के कारखानों में काम करनेवाले कामगार उनके सदस्य थे, जबकि उपभोक्ता सहकारों के कारखानों में काम करनेवाले मात्र कामगार थे और उन्हें वे लाभ प्राप्त नहीं थे जो सदस्यों को मिलते हैं। सैद्धांतिक कारणों के अलावा, इंग्लैण्ड में दो कारखानों के बीच स्पर्धा थी, जहाँ अधिक कार्यक्षम को जीवित रहना था। लेकिन भारत में अवस्थाएँ भिन्न हैं। भारत में ये साधारण प्रशोधन कार्य अब भी स्वतंत्र कारीगर अपने घरों में करते हैं, और देश की कुल आवश्यकता के अच्छे-खासे हिस्से की पूर्ति करते हैं।

उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन

उपभोक्ता भण्डारों द्वारा प्रशोधन कार्य का संगठन करने पर स्वतंत्र कारीगरों के काफी तादाद में बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम लाभ कमाने की दृष्टि से वे यंत्रों की सहायता

से उत्पादन कार्य करने की ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में प्रशोधन कार्य करने का भी आस-पास के देहातो पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि गाँवों के बहुत से कारीगर अपने उत्पादनों की बिक्री के लिए शहरी बाजारों पर निर्भर करते हैं। अतएव उपभोक्ता भण्डारों द्वारा प्रशोधन कार्य अपवाद स्वरूप ही अपनाया जा सकता है, निरपवाद नहीं। नगरो तक में प्रशोधन कार्य अमानेवाले उपभोक्ता भण्डार को वहाँ के सुस्थापित मौजूदा उत्पादन संस्थानों से टक्कर लेनी पड़ेगी। इस टक्कर में डटे रहने के लिए उपभोक्ता भण्डारों को दीर्घ स्तरीय उत्पादन का तरीका अपनाना पड़ेगा, जोकि प्राथमिकों के लिए सम्भव नहीं है।

थोक काम करनेवाले ही प्राथमिक भण्डारों अथवा अपनी शाखाओं के जरिये सक्षम वितरण व्यवस्था करने के बाद इस सम्बन्ध में सोच सकते हैं। चावल, चीनी और तेल जैसी उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन के लिए सहकारी बिक्री समितियाँ भी प्रशोधन कार्य कर रही हैं। व्यक्तियों और संस्थानिक अभिकरणों से स्पर्धा होने की दृष्टि से किसी नगर में थोक काम करनेवाली समिति अपनी आवश्यकताओं की बिक्री समितियों से ये चीजे लेकर लाभदायक रूप में पूर्ति कर सकती है। इसी प्रकार चूँकि भारत में सहकारी उत्पादक समितियों के काम का अच्छा रिकार्ड है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों का उत्पादक सहकारी समितियों से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

उत्पादन और उपभोग

फिलहाल जिस उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन परम्परागत तरीके से हो रहा है उसका आधुनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादन करने के लिए अवस्थाएँ अनुकूल नहीं हैं। ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में उक्त कथन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इसीलिए तीसरी पंचसाला योजना में चन्द प्रकार की सामग्री की आंशिक पूर्ति के लिए मौजूदा उपकरणों की सहायता से ही सघन

उत्पादन करने की योजना बनायी गयी है। यदि यही सामग्री राज्य सरकार के अन्तर्गत संगठित अभिकरणों की सहायता से आधुनिक प्रक्रियाओं के जरिये भी तैयार की जाती है तो परम्परागत उद्योगों के सामने निश्चय ही भयकर स्पर्धा खड़ी होनेवाली है। ऐसी अवस्था में इन दोनों का सम्बन्ध नियमित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। इसलिए सुफल-प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि वर्तमान उत्पादक सहकारिताओं और उपभोक्ता संगठनों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जाय।

परम्परागत प्रक्रियाओं के जरिये सफल उत्पादन का संगठन उपभोक्ता की ओर से किया जा सकता है। यदि जो कुछ पैदा किया जाता है वह बिना किसी दिक्कत के खपाया नहीं जा सकता तो उत्पादन का संगठन करने से कोई लाभ नहीं है। भूतकाल में ग्राम उत्पादन को इसलिए कष्ट उठाना पड़ा कि उसका उपभोक्ताओं के साथ समन्वय नहीं था। उपभोक्ताओं को अच्छे गुणस्तर का माल उपयुक्त भावों पर मिले, इसके लिए सभी प्रकार की सामग्री का उत्पादन उपभोग पद्धति के हिसाब से आयोजित होना चाहिये।

लोक अभिक्रम के साथ आयोजन

अब से आगे खादी-ग्रामोद्योगों के विकास सम्बन्धी काम को क्षेत्रों के विकास-कार्य के साथ जोड़ना है और उसे लोक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। क्षेत्रीय स्वावलम्बन के लिए काम करने का निश्चय किया गया है। प्रत्येक प्राथमिक इकाई को ग्राम इकाई कहा जाता है। उसकी आबादी ५,००० होती है और कार्य क्षेत्र एक ग्राम पंचायत के समान। क्षेत्रीय स्वावलम्बन के लिए आयोजन करनेवाला माध्यम पंचायत समिति हो सकती है। इसके अन्तर्गत १०-१२ ग्राम पंचायत हो सकती हैं। कार्यक्रम में इस बात की कल्पना की गयी है कि ग्राम समाज स्वयम् अपनी विकास योजना बनायेगा और चलायेगा। समाज को उपभोग के लिए

जिन परमावश्यक चीजों की आवश्यकता हो उनका उत्पादन स्थानीय माधन-स्रोतों का उपयोग करते हुए मगठित किया जाना चाहिये। आवश्यकता से अधिक माल पास-पड़ोस के क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था में बिक्री की समस्या सहल होगी और स्थानीय साधन-स्रोतों की अनुपलब्धि से बचा जा सकेगा।

कार्यक्रम के लिए अभिकरण

दूसरी पांचसाला योजना में भी इस प्रकार के प्रयास किये गये, जब इस तरह के समन्वित रूप में काम का मगठन करने के लिए २६ मार्गदर्शी परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयी। लेकिन, अनेक कारणों वश इन मार्गदर्शी परियोजनाओं में, दुर्भाग्य से, वाञ्छित फल प्राप्ति नहीं हुई। देश में फिलहाल जैसी अवस्थाएँ हैं, वे इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होने से इस कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अगुआई प्राप्त की जा सकती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ और जिला परिषदे देश भर में स्थापित हो चुकी हैं अथवा यदि कहीं नहीं हुई हैं तो की जायेगी। ये स्थानीय सगठन अपने स्वयम् के क्षेत्रों के आर्थिक विकास की योजनाएँ बनायेगे। ये सगठन शीघ्र ही महसूस करेंगे कि यदि लोग स्थानीय रूप से उत्पादित माल का उपभोग नहीं करते हैं तो उस माल के लिए अन्यत्र बाजार नहीं होगा। और, अगर उपभोग की दृष्टि से उत्पादन की योजना नहीं बनायी जाती है तो कोई भी उत्पादन गतिविधि अधिक समय तक चल नहीं सकती। इसी बुनियादी दृष्टिकोण को लेकर ग्राम इकाई कार्यक्रम शुरू किया गया है।

ग्राम इकाई कार्यक्रम की कार्य पद्धति अभी तक अस्पष्टावस्था में ही है। कहा जाता है कि ग्राम इकाई का काम सहकारी ढंग से चलेगा। सेवा सहकार, सहकारी उधार समिति, बहुदेशीय सहकारी समिति, सहकारी

भण्डार, सहकारी कृषि समिति आदि जैसी अनेक सहकारी समितियाँ सुमयोजित कार्यक्रम में शामिल होगी। विकास आयुक्तों के सम्मेलन की सिफारिशों में कहा गया है कि ग्राम इकाई सगठन में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और सहकारी समितियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह 'इकाई सगठन' क्या है। ग्राम इकाई के लिए उपनियम बनाये जा रहे हैं। ये उपनियम ऋण, उत्पादन, विक्रय-व्यवस्था, आयोजन, प्रचार-प्रसार आदि के सम्बन्ध में होंगे। इससे इंगित मिलता है कि इकाई सगठन एक सहकारी समिति होगी जिसके अन्तर्गत ये सब कार्यशीलताएँ आयेगी। कभी-कभी कहा जाता है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति यह काम करेगी। क्षेत्रीय कार्यकर्ता सफलतापूर्वक कार्यक्रम कार्यान्वित कर सके, इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम की रूप-रखा विल्कुल स्पष्ट हो।

सेवा सहकार

क्या ग्राम सेवा सहकार ग्राम इकाई कार्यक्रम कार्यान्वित कर सकता है? सेवा सहकारी समिति के अन्तर्गत अब तक ये विषय आते हैं ऋण देना, ऋण की उपयोगिता के सम्बन्ध में निगरानी, उत्पादन की बिक्री करके ऋणों की पुनर्वाप्ति, उर्वरक, बीज आदि की पूर्ति, सदस्यों को उपभोक्ता सामग्री की पूर्ति, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन। सहकारिताओं के कामों में ग्राम इकाई कार्यक्रम भी शामिल कर देने का अर्थ है उनका भार और भी ज्यादा कर देना। एक सेवा सहकार के प्रबन्धक के लिए यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि वह सभी विभागों को एक साथ सम्हाल सके, क्योंकि ये सभी काम व्यापारिक ढंग से चलाने पड़ेगे।

ग्राम इकाई के लिए अलग से सहकारी समितियों का गठन करना भी उपयुक्त नहीं है। मौजूदा सस्थाओं के काम में उपयुक्त विभाजन करने और उच्च आयोजक माध्यमों की ओर से मार्गदर्शन मिलने पर कार्यक्रम, एक

नया सगठन खड़ा करने की अपेक्षा, अधिक अच्छी तरह कार्यान्वित किया जा सकेगा, क्योंकि ग्राम स्तर पर विकास कार्य में लगे अभिकरणों के साथ मिलने में उसे कुछ समय तो लग ही जायेगा।

अब हम ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ग्राम इकाई क्षेत्र में मौजूदा अभिकरणों की भूमिका पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इकाई क्षेत्र के निवासियों द्वारा ग्राम इकाई कार्यक्रम चलाने का निर्णय करने के बाद उपलब्ध कच्ची सामग्री और इकाई क्षेत्र में उपभोक्ता सामान की आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण करना पड़ेगा। यह सर्वेक्षण ग्राम सहायक करेगा। सर्वेक्षण करने के बाद वह सर्वेक्षण का प्रतिवेदन ग्राम पचायत के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

क्षेत्रीय स्वावलम्बन

यह ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ तक हो सके उपलब्ध कच्ची सामग्री का ग्राम इकाई में ही प्रशोधन हो तथा जिन उपभोक्ता सामानों की माँग हो उनके उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री पैदा की जाय। उत्पादन की योजना बनाने और उपभोग-आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के बाद ग्राम पचायत को चाहिये कि वह इकाई में आवश्यकता से ज्यादा तथा कमीवाली सामग्री के सम्बन्ध में पचायत समिति को जानकारी करवाये। पचायत समिति को चाहिये कि वह इस जानकारी के आधार पर उन इकाइयों में उक्त अतिरिक्त माल के वितरण की योजना बनाये, जिनमें कमी हो। क्षेत्रीय स्वावलम्बन का सम्बोधन फिलहाल पचायत समिति के क्षेत्र तक रखा जा सकता है।

उत्पादन का सगठन मद के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री और कौशल के अनुसार एक इकाई में तेल पेराई की इकाई हो सकती है तो दूसरी में गुड-खाण्डसारी उत्पादन इकाई। इसी प्रकार किसी तीसरी में चर्मोद्योग उत्पादन कार्य चलाया जा सकता है। प्रत्येक

इकाई में एक खादी उत्पादन केन्द्र और एक अन्न प्रशोधन केन्द्र हो सकता है। ये सभी उत्पादन इकाइयों ग्राम तौर पर वित्तीय तथा प्राविधिक सहायताएँ प्राप्त कराते हुए सहकारी समितियों के रूप में सगठित की जा सकती हैं। यद्यपि ग्राम पचायतों का आयोजन और प्रचार-प्रसार से ताल्लुक रहेगा, तथापि इकाई की आवादी में उपभोक्ता सामग्री का वस्तुतः वितरण करना उनके लिए सम्भव नहीं होगा। वास्तविक वितरण के लिए अन्य कोई सगठन खड़ा करना होगा। अलग-अलग उत्पादन इकाइयों इस काम के लिए उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि एक ग्राहक अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिए प्रत्येक उत्पादन इकाई से चीज लेने के लिए नहीं जाने-वाला है। उपभोक्ता यह पसन्द करेगा कि उसकी आवश्यकता की अधिकांश सामग्री एक स्थान पर मिल जाय।

उपभोक्ता सहकारी समिति

इस काम के लिए प्रत्येक इकाई में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का गठन किया जा सकता है, जोकि न केवल उत्पादन सामान की बल्कि इकाई की आवश्यकतावाली पास-पड़ोस की इकाइयों में उत्पादित चीजों की बिक्री भी करेगा। इस प्रकार के उपभोक्ता भण्डारों को सहकारी समिति के रूप में गठित करना सर्वोत्तम होगा। उपभोक्ता सहकारी समिति का काम विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा तैयार माल की बिक्री करना ही हो सकता है, उत्पादन समितियों अपना काम उत्पादन करने तक ही सीमित रख सकती हैं। सहकारी भण्डार किस प्रकार की और किस परिमाण में चीजें रखेगा, इसका निर्धारण ग्राम पचायत कर सकती है। यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठ सकता है—इन भण्डारों को आर्थिक दृष्टि से जीवित रखने के सम्बन्ध में। सहकारी भण्डार से १,००० परिवारों अथवा ५,००० व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोग-स्तर की दृष्टि से देखन पर यह कहा जा सकता है कि १,००० परिवारों का वार्षिक उपभोग

खर्च दो लाख रुपये के करीब होगा। यह मानते हुए कि आम जरूरतों का ५० प्रति शत हिस्सा सहकारी भण्डार पूरा करेगा, इसलिए उसका जितना लेन-देन होगा, उससे भण्डार आर्थिक दृष्टि से प्राणवान होगा।

स्थानीय उत्पादनो का वाणिज्य

सहकारी भण्डार इकाई के सभी परिवारों को अपने सदस्य बनायेगे। सदस्यों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और अधिकतम सम्भव सीमा तक उन्हें पूरी करने की कोशिश करना भण्डार का कर्तव्य होगा। भण्डार केवल ग्राम उत्पाद केन्द्रों के उत्पादनों की ही बिक्री करेगा। इस प्रकार वह उपभोक्ताओं को सामग्री की शुद्धता के सम्बन्ध में आश्वस्त करेगा।

भण्डार को चाहिये कि वह आवश्यक चीजें केवल पचायत समिति के अन्दर की उत्पादन इकाइयों से ही खरीदे। यदि कोई परमावश्यक उत्पादन पचायत समिति के क्षेत्र में तैयार न होता हो तो वैसी अवस्था में वह बाहर से खरीद कर सकता है। किसी भी उत्पादक से खरीद करने में भण्डार को स्वतंत्रता होनी चाहिये। उत्पादक समिति को जोकि उपभोक्ता समिति में सदस्य है, यह कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देगा। उपभोक्ता सहकारी भण्डार के निदेशक-मण्डल में उत्पादकों का प्रतिनिधित्व होने से उपभोक्ता समिति में किसी भी

उत्पादक समिति के हितों की रक्षा की जा सकती है। सहकारी भण्डार या तो उत्पादक समितियों से प्रचलित बाजार भाव पर माल की खरीद अपनी खरीद के रूप में कर सकता है अथवा फिर उनके अभिकर्ता के रूप में परेपण हिसाब पर माल की बिक्री कर सकता है। इस प्रकार के उपभोक्ता भण्डार को एक दूकान-सह-गोदाम, कुछ व्यवस्थापकीय कर्मचारियों और सचालन पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी।

सरकार की भूमिका

भारत में उपभोक्ता सहकार का अध्ययन करनेवाले दल ने सिफारिश की है कि राज्य को हिस्सा पूंजी में भाग लेना चाहिये, गोदाम, व्यवस्थापकीय कर्मचारियों और सचालन पूंजी के लिए ऋण देना चाहिये तथा उपदान प्रदान करना चाहिये। तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान इसने २,५०० सहकारी भण्डारों की स्थापना करने की सिफारिश की है। इसी अवधि में ३,००० ग्राम इकाइयाँ स्थापित करने की भी योजना है। कुछ सुस्थापित इकाइयों में वितरक सगठन काम कर रहे होंगे, जहाँ उक्त प्रकार के भण्डारों की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार प्रस्तावित प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की संख्या मोटे तौर पर योजना की अवधि में प्रस्तावित इकाइयों की संख्या के समान ही होगी।

खाद्यान्न-फसलों की प्रति एकड़ कम उपज और नकद फसलों की प्रधानता होने के कारण राज्य में अनाज की कमी है। अनुमान है कि राज्य में खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन २० लाख टन है, जबकि उसकी वार्षिक आवश्यकता ३१ लाख टन है।

—टेक्नो-इकनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात : नेशनल
कॉउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली।

ग्रामीण क्षेत्रों में गैस संयंत्र

दत्तात्रेय ना. वान्देकर

मानवीय मल-मूत्र तथा गोबर और अन्य कार्बनिक सामग्री का उपयोग—जो बेकार जाती हो उसका—करनेवाले सामुदायिक गैस संयंत्रों पर अनुसंधान करना आवश्यक है। इसके साथ ही गैस संयंत्रों के स्थल पर ही गैस का सशुद्ध कर मिलिण्डरो में भरने तथा गैस निर्माण की प्रक्रिया को सरल और सस्ती बनाने की भी आवश्यकता है।

जुलाई १९६३ के स्वार्दी ग्रामोद्योग में प्रकाशित श्री हर्षवदन जयकिशनदास दलाल का 'गोबर गैस संयंत्र से बचत' एक विचारोत्तेजक लेख है। उक्त लेख में वर्धा के निकट दत्तापुर कोठी बस्ती में स्थापित गोबर गैस संयंत्र के निर्माण और संचालन सम्बन्धी आकड़ों पर चर्चा की गयी है। श्री दलाल ने हिसाब लगाया है कि भोजन बनाने के लिए संयंत्र से प्राप्त गैस का इस्तेमाल करने पर ईंधन की कीमत के रूप में ८०९ रुपये की बचत हुई है अथवा संयंत्र पर विनियोजित ४,३०० रुपये पर १८ ८ प्रति शत विशुद्ध प्रतिफल मिला है। यह तो रखा उनका रुपये-पैसे की शब्दावली में लगाया गया हिसाब। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य लाभ भी बताये हैं, जो आसानी से रुपये-पैसे में रूपान्तरित नहीं किये जा सकते। उनके अनुसार ये लाभ हैं, धूँआँ से मुक्ति, दुग्धी नाइट्रोजन के साथ पाचित खाद की प्राप्ति, इस प्रकार की ५० प्रति शत ज्यादा खाद का लाभ और दीर्घ के लिए जंगलों का नष्ट हो जाने से आरक्षण।

योजना आयोग की भूमिका

हर गाँव में मानव मल-मूत्र और गोबर का साथ-साथ इस्तेमाल करने में समर्थ गैस संयंत्रों के साथ शौचालय निर्मित करने तथा गाँव की प्रत्येक झोपड़ी में भोजन पकाने के लिए गैस पहुँचाने की व्यवस्था के लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम को विस्तृत व व्यापक रूप से अपनाने के लिए सरकार ने अभी तक किसी खास पैमाने पर कोई आयोजन नहीं किया है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सामुदायिक विकास खण्डों ने यहाँ-वहाँ

इस प्रकार के शौचालय तथा गैस संयंत्र स्थापित करने एवम् प्राप्त गैस का भोजन पकाने के लिए जो थोड़े-बहुत प्रयास किये, वे प्रयोग के तौर पर थे, और ये प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं। इन प्रयोगों के फलस्वरूप ग्राम-पाम के ग्रामीणों ने ऐसी सुविधाओं की माँग की है।

लेकिन अपने सीमित साधन-स्रोतों के कारण न तो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ही और न सामुदायिक विकास खण्ड ही इस स्थिति में हैं कि वे किसी विस्तृत पैमाने पर यह कार्यक्रम चला सकें। यह काम योजना आयोग के लिए है कि वह इस कार्यक्रम के लिए योजना बनाये और फिर उसके लिए आवश्यक प्रावधान रखे। प्राथमिक रूप से केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर स्वास्थ्य विभागों का यह कर्तव्य है कि वे देश के लगभग छ लाख गाँवों में सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था करें। यदि प्रत्येक ग्राम में इतनी बड़ी क्षमतावाले इस स्तर पर गैस संयंत्र स्थापित कर दिये जायें जिनमें गाँव के लोगों का मल-मूत्र, गोबर तथा अन्य बेकार जानेवाली कार्बनिक सामग्री समा जाय तो उक्त कर्तव्य दक्षता पूर्वक पूरा किया जा सकेगा। यद्यपि यह एक भारी काम है, तथापि, स्थानीय संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंप कर इसका अच्छी तरह विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है।

ऊपर बताये गये फायदों के अलावा एक और भी लाभ है, जो उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। गैस संयंत्र से प्रत्येक गाँव में शौचालयों का निर्माण हो सकेगा, जोकि हमारी बहिनों की लाज की समस्या हल करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। गाँवों के ये शौचालय

बम्बई जैसे नगरों के शोचालयों के समान सगमरमर के पत्थरों में बने और खपरेलो से छाये हुए होने चाहिये। इन शोचालयों के चारों ओर बगीचा भी होना चाहिये। हमें ग्रामीणों को उनका उपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी। खादी ग्रामोद्योग में प्रकाशित अपने एक लेख में मैंने जो हिसाब लगाया है उसके अनुसार इस स्रोत से हमारे गाँवों में करीब ३५ करोड़ घनफुट गैस का उत्पादन प्रति दिन हो सकेगा। श्री दलाल के हिसाब के अनुसार इसका मतलब है प्रति दिन १४ लाख मन लकड़ी की बचत। अब गाँवों में महिलाओं की समस्या हल करने और मानव मल-मूत्र से बने गैस का भोजन पकाने के लिए उपयोग करने पर क्यों न उपयुक्त जोर दिया जाय।

प्राविधिक कर्मचारी

प्राथमिक रूप से जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि ग्रामीणों को चन्द प्रकार के विचारों और स्वभावों का प्रशिक्षण दिया जाय तथा उनमें नागरिक भावना भरी जाय। यह काम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में स्थानीय सस्थाएँ कर सकती हैं। इसी के समान आवश्यक और महत्वपूर्ण सवाल है लोगों को काफी तादाद में गैस सयत्र की तकनीकों में प्रशिक्षण देने का। इस काम के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में प्रशिक्षण सस्थाएँ खोलें। जब तक उपयुक्त तादाद में प्राविधिक कर्मचारी न हों—जोकि न केवल सयत्रों की स्थापना में बल्कि आगे चल कर उनकी मरम्मत आदि में भी सहायता करेंगे—तब तक कार्यक्रम सफल नहीं होगा। फिलहाल इन तकनीकों की बहुत ही कमी है। मैं ऐसी कई ग्राम पंचायतों को जानता हूँ जो गैस सयत्र स्थापित करने की इच्छुक हैं, लेकिन वे यह नहीं जानती कि प्राविधिक तथा अन्य सहायता कहाँ से प्राप्त करें। वस्तुतः कहीं भी ऐसी कोई सस्था नहीं है कि उससे वे ऐसी सहायता प्राप्त कर सकें।

अनुसंधान

इसके अलावा केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारों को चाहिये कि वे इस सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य के लिए

सस्थाओं की स्थापना करें। अन्वेषण के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। नागपुर स्थित 'सेण्ट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट' ने बृहत्तर बम्बई के बोरिवली नामक स्थान पर एक दिशा में मामूली कार्यरम्भ किया है। यह सस्था एक इस प्रकार के गोबर गैस सयत्र की डिजाइन बनाने में सफल हुई है जिसकी लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि प्राप्त की गयी है। इस सयत्र से इतना गैस तैयार हो जाता है, जो एक सात सदस्यीय परिवार की ईंधन सम्बन्धी सभी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त है। इस सयत्र की लागत ६५० रुपये है जो आगे अनुसंधान करके और भी कम की जा सकेगी। जो है सो ठीक है, तथापि, जरूरत इस बात की है कि मानव मल-मूत्र, गोबर तथा बेकार जानेवाली अन्य कार्बनिक सामग्री का इस्तेमाल कर सके ऐसे सामुदायिक गैस सयत्र के सम्बन्ध में अन्वेषण किया जाय। मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि इस विस्तृत क्षेत्र के सम्बन्ध में देश भर में कहीं भी अन्वेषण हो रहा है।

दूसरा प्रश्न है कि गैस को किस प्रकार गैस सयत्र के स्थान पर ही सदाबित कर सिलिण्डर में भरा जाय और किस प्रकार इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल तथा सस्ती बनाया जाय। अनुसंधान सस्थाओं के लिए भी यह एक समस्या है। गैस की नालियाँ लगाकर गाँव के प्रत्येक घर में गैस पहुँचाना बहुत खर्चीला पड़ेगा। यह अत्यधिक खर्चवाला वितरण गैस सयत्रों को लोक-प्रिय बनाने में एक बाधा है। जब तक इस कमी को दूर करने के लिए कोई तरीका न खोज निकाला जाय, तब तक वास्तविक प्रगति की आशा नहीं की जा सकती। घरेलू इकाई में हो सकता है कि यह समस्या खड़ी न हो, लेकिन सामुदायिक सयत्रों की योजना बनाते वक्त यह खड़ी हो जाती है। चन्द महीनों पूर्व मैंने 'सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट' और 'भारतीय कृषिक अनुसंधान सस्था', नयी दिल्ली दोनों के समक्ष ही यह समस्या रखी है।

अगर और आगे का कोई अनुसंधान कार्य हो तो वह आवश्यक रूप से ही समन्वित होना चाहिये। प्राप्त

परिणामों की जानकारी फैलाने के लिए प्रबन्ध किये जाने चाहिये। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि एक केन्द्रीय संस्था तथा प्रत्येक राज्य में एक-एक संस्था इसी काम के लिए हो। ऐसी संस्थाओं को चाहिये कि वे अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के साथ सहयोग करे।

सामुदायिक इकाइयाँ

पारिवारिक इकाई के लिए प्रारम्भिक ६५० रुपये की लागत में परिवार के लिए एक या दो शौचालय बनाने का खर्च शामिल नहीं है। इन शौचालयों की स्थापना बहुत ही आवश्यक है। शौचालयों की लागत करीब ६०० रुपये आ सकती है। इस प्रकार कुल विनियोजन १,२५० रुपये होगा। एक औसत ग्रामीण परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल होगा। गाँव में मुश्किल से एक प्रति शत परिवार इतना विनियोजन करने में और करने के लिए, समर्थ तथा तैयार होंगे। आदिवासी क्षेत्रों में तो कोई समर्थ होगा ही नहीं। इस प्रकार इन पारिवारिक इकाइयों से ग्राम सफाई, महिलाओं की लाज, मूल्यवान पेड़ों और जंगलों को गैर-कानूनी तौर से काटने की समस्या हल नहीं हो सकती। इस बात पर जोर देना चाहिये कि स्थानीय ग्राम पंचायतें सामूहिक इकाइयाँ स्थापित करें और उनके रख-रखाव का काम देखें। इन इकाइयों की लागत काफी अधिक होगी। लेकिन इन संस्थाओं को इन कामों के लिए ऋण दिया जा सकता है और इन सयंत्रों से उक्त संस्थाओं को जो सोन खाद प्राप्त होगी, उससे प्राप्त आमदनी से ऋणों की वापसी की जा सकेगी। भोजन बनाने के लिए गाँव के हरेक घर को गैस मुफ्त में दी जाय अन्यथा ईंधन के लिए मूल्यवान पेड़ों की कटाई कानूनी या गैर कानूनी रूप से होती ही रहेगी।

ईंधन की समस्या का समाधान

गाँव की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने और उसकी जरूरत के उपकरण बनाने के लिए ग्राम-जंगल उगाने का विचार व्यावहारिक नहीं है। प्रति वर्ष प्रत्येक गाँव को कितने ईंधन और इमारती काठ की

आवश्यकता पड़ेगी तथा इस काम के लिए कितने जंगली इलाके की जरूरत होगी, इसका कहीं भी हिसाब नहीं लगाया गया है। एक दूसरा सवाल यह है कि क्या हरेक गाँव में इस काम के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है? और फिर, क्या इस प्रकार के जंगलों से गाँव के गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त ईंधन मिल सकेगा और जितने काल में—उदाहरणार्थ २० वर्ष—यह जंगल बढ़ कर ईंधन देने लायक होगा, उतनी अवधि के लिए ईंधन की व्यवस्था का क्या इन्तजाम किया जायगा? मैं ग्राम-जंगल के विपक्ष में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक गाँव में उसका सौन्दर्य बढ़ाने के लिए अधिकाधिक पेड़ हो अर्थात् गाँवों में पेड़ ईंधन के लिए न हो कर फल-फूल और छाया तथा ठंड प्रदान करने के लिए हो। ईंधन की समस्या का समाधान गैस सयंत्रों से ही हो सकता है।

हमारी ३५ करोड़ ग्रामीण आबादी को प्रति दिन भोजन बनाने के लिए ४ अरब १० करोड़ घनफुट गैस की आवश्यकता होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सयंत्रों से उसका उत्पादन ४ अरब ३५ करोड़ घनफुट होगा। गैस सयंत्रों के बीच में बन्द पड़ जाने जैसे मामलों का सामना करने के लिए २५ करोड़ घनफुट का सीमान्त (मार्जिन) रखना पड़ेगा। इस प्रकार प्रायः गैस भोजन पकाने सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त भर है। इसलिए इन सयंत्रों में प्राप्त गैस को मिचाईया घर-गली में रोजनी करने जैसे कामों में प्रयुक्त न किया जाय।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को चाहिये कि वह प्रत्येक ग्राम इकाई के क्षेत्र में आनेवाले गाँवों में, इकाई की स्वीकृति देते वक्त, सामुदायिक गैस सयंत्र स्थापित करने की बात पर जोर दे। ग्राम इकाइयों को अगर कोई परिवार अपनी पारिवारिक इकाई स्थापित करने का इच्छुक हो तो उसे सहायता देनी चाहिये। इकाइयों के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें सार्वजनिक और निजी शौचालय तथा आवश्यक गैस सयंत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त सहायता भी शामिल करनी चाहिये।

औद्योगिक सहकारी समितियाँ

मसूदा अली मिर्जा

हमारे देश में औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास की गति उन्हें सरकारी सहायता देकर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लघु उद्योगों का विस्तार कर अब तक के अछूते क्षेत्रों में उनका प्रसार किया जा रहा है। इन सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध करने की दिशा में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इन समितियों को अधिकाधिक मात्रा में ऋण प्राप्त हो सके, इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करने के अलावा अलग औद्योगिक सहकारी बैंकों का भी गठन किया जा रहा है।

औद्योगिक सहकारी समितियों के संगठन का तात्पर्य

केवल शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि लाभ में भाग-दारी के लिए गठन भी है। तथापि साझेदारों को लाभ के साथ हानि में भी भागीदार होना पड़ता है। औद्योगिक साझेदारी का श्रेय फ्रांस के फोरियर (Foulier) महोदय को है, जिन्होंने मजदूरी को घृणात्मक बनाने की अपेक्षा आकर्षक बनाने के सिद्धान्त प्रतिपादित किये। उन्होंने श्रमिक को पूँजी का साझेदार, न कि केवल उसका चाकर, बनाने के विचार को हकीकत में परिवर्तित किया। सहकारी समिति में सदस्य या तो अपने घरों में अथवा सहकारी समिति के आवाते में उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह सर्वाधिक प्रचलित समिति उस तरह की है जो अपने सदस्यों को कच्चे माल, बिक्री सुविधाएँ और सरजाम प्रदान करती है। औद्योगिक सहकारी समितियों का प्रमुख उद्देश्य है अनेकानेक उत्पादकों को संगठित करना ताकि उत्पादन लागत कम की जा सके, काम की तकनीक सुधारी जा सके, मानक उत्पादन हो, आदि।

औद्योगिक सहकारिता

हमारे देश में कृषि सहकारिता की अपेक्षा औद्योगिक सहकारिता की शुरुआत बहुत हाल ही में हुई है। सरकारी समर्थन के परिणामस्वरूप सहकार के क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है और बड़ी संख्या में औद्योगिक सहकारी

समितियाँ गठित हुई हैं जो मुख्यतः तीन प्रकार की हैं (अ) वे समितियाँ जो स्वयं उत्पादन कार्य करती हैं, (आ) वे समितियाँ जो अपने सदस्यों को अनेक सेवाएँ प्रदान करती हैं जैसे ऋण की व्यवस्था, कच्चे माल और मशीनों की पूर्ति, आदि, और (इ) वे समितियाँ जो अपने सदस्यों को अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कार्य-गृह जैसी सामान्य सुविधाएँ भी प्रदान करती हैं।

वित्त

लघु स्तरीय उद्योगों के योजनाबद्ध विकास और उन्नत सरजाम तथा तकनीकों का समावेश करने से सहकारी समितियाँ नये क्षेत्रों में भी गठित की जा रही हैं जैसे (१) रंग के उत्पादन के लिए औजार गृह, पुर्जे बनाने के लिए औजार और कार्यगृह, (२) कच्चे माल की प्रारम्भिक प्रशोधन प्रक्रियाएँ, जैसे कताई, बेलनी पर लपेटना और ऊन मिश्रण आदि, (३) विशेष प्रक्रिया जैसे उष्मा-उपचार, और विद्युत-लेपन, (४) परीक्षण और समापन, तथा (५) सहायक सामग्री आदि के उत्पादन की माँग को पूरा करने के लिए संयुक्त कार्य।

सरकार ने संचालन और स्थायी पूँजी के निमित्त ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की अनेक पद्धतियाँ बनायी हैं। जून १९६२ तक इस प्रकार का ऋण इन समितियों के कुल ऋण के २० प्रतिशत से अधिक रहा और अधिकतर ऋण बैंक से रहे जो सरल

किस्तों में १० वर्षों में लौटाने पड़ते हैं। कारीगरों को हिस्सा खरीदने और उनके द्वारा समितियों के अश-पूँजी आधार को मजबूत करने के लिए सरकार दो से चार सालों के लिए अश-पूँजी ऋण दे रही है, जिस कि सदस्यों की आय से प्राप्त मासिक योगदान में से चुकाना पड़ता है। कुछ मामलों में अश-पूँजी ऋण उन सहकारी समितियों को दे दिया जाता है जो सदस्यों को प्रमाण-पत्र प्रदान करती हैं और सदस्य-गण उस रकम का पुनः अशों के रूप में विनियोजन करते हैं। अन्य मामलों में सदस्यों के नाम पर व्यक्तिगत रूप से ऋण मजूर किया जाता है, जिन्हें नकद के बजाय अश प्रमाण-पत्र मिलता है किन्तु सरकार के द्वारा अदा करने के लिए वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। राज्य सरकारों, दीर्घ काल से ही जहाँ प्राथमिक समितियाँ इतनी कमजोर हैं कि अत्यधिक योगदान नहीं कर सकती हैं, वहाँ शिखर एवं सचीय समितियों की अश-पूँजी में भागीदार होती हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों की अश-पूँजी में राज्य साझेदारी विशेष कर असम, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में चालू हैं।

स्टेट बैंक की भूमिका

स्टेट बैंक ने अपनी नीति के परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप लघु स्तरीय उद्योगों की आवश्यकताएँ पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना शुरू कर दिया है। औद्योगिक सहकारी बैंक सहकारी समितियों के पंजीयक की पूर्ण अनुमति के बिना ऐसा करने में असमर्थ थे। स्टेट बैंक और उसकी सहायक शाखाओं द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को दिये गये ऋण के लिए व्यापारिक सूद दर योजना और ९० प्रति शत गारंटी योजना भी लागू की गयी है। ऐसा सोचा जाता है कि इससे औद्योगिक समितियों को बड़ी रकम ऋण के रूप में प्राप्त होने लगेगी।

सामान्य स्थिति में औद्योगिक सहकारी समितियों को अपनी ऋण आवश्यकता के लिए केन्द्रीय सहकारी

बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों से आग्रह करना चाहिये। तथापि, ये बैंक कृषि समितियों में पहले से ही रत होने और अपने सीमित स्रोतों के कारण ऐसी समितियों की ओर सामान्यतः पर्याप्त सहायता नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। इस स्रोत से औद्योगिक सहकारी समितियों को सन् १९६२ में ९ करोड़ १५ लाख रुपये ऋण प्राप्त हुआ। इसलिए सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये गये हैं ताकि वे औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय मदद के लिए अपनी निधि का एक भाग सुरक्षित रख सकें, औद्योगिक ऋण की व्यवस्था के लिए एक औद्योगिक उप-समिति का, जिसमें औद्योगिक सहकारी समितियों के एक या दो सदस्य होंगे, गठन कर सकें, अपने प्रबन्ध मण्डल में औद्योगिक सहकारी समितियों के एक या दो प्रतिनिधियों को रखने की अनुमति दे सकें और औद्योगिक सहकारिता से सम्बन्धित मामलों की देख-रेख के लिए एक उप-प्रबन्धक की, जिसकी एक या दो निरीक्षक मदद करेंगे, नियुक्ति कर सकें।

केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों को औद्योगिक सहकारी समितियों को रियायती सूद दर पर—जैसा कि राज्य सरकारों ऐसी समितियों को ऋण देने पर वसूल करती हैं—अतिरिक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार राज्य सरकारों के जरिये सहकारी बैंकों को रियायती दर अर्थात् २½ प्रति शत और सामान्य दर के अन्तर को उपदान देकर पूरा करती है। यह योजना केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को दिये गये २ लाख रुपये तक के सभी लघु-कालीन और मध्य-कालीन ऋणों पर लागू होती है।

औद्योगिक सहकारी बैंक

वर्तमान सहकारी बैंक—जिसमें राज्य स्तर पर शिखर बैंक और जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक सम्मिलित हैं—मुख्यतः कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने में लगे हुए हैं। औद्योगिक सहकारी समितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग बैंक अर्थात् औद्योगिक सहकारी

बैंक स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य स्तर पर मैसूर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मद्रास में इस तरह के चार बैंक स्थापित किये जा चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और मैसूर में जिला स्तर पर सहकारी बैंक स्थापित किये गये हैं। जिला स्तर पर हर औद्योगिक इकाई को सदस्य बनने का अवसर प्रदान किया गया है ताकि जमा के रूप में अधिक रकम प्राप्त की जा सके।

आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक सहकारी समितियाँ दो अधिनियमों द्वारा प्रशासित हैं। आन्ध्र और तेलंगाना क्षेत्र की सहकारी समितियाँ क्रमशः १९३२ के मद्रास सहकारी समिति अधिनियम और १९५२ के हैदराबाद सहकारी समिति अधिनियम से प्रशासित हैं। दोनों क्षेत्रों में सहकारी समितियों के उपनियम उपर्युक्त दो अधिनियमों की धाराओं के अनुसार उचित रूप में तैयार किये गये हैं। पंजीयक के समस्त अधिकार, लेखेक्षण से सम्बन्धित अधिकारों को छोड़ कर, औद्योगिक विभाग के अधिकारियों को प्रदान किये गये हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सन् १९६२ में १,०९९ औद्योगिक सहकारी समितियाँ थी जिनके २६,७५६ सदस्य थे और चुकता अंश पूँजी ११,०३,१४२ रुपये थी। सन् १९६०-६१ के सहकारिता वर्ष में इन समितियों ने १६ लाख रुपये मूल्य का उत्पादन किया। इन समितियों को आन्ध्र प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग मण्डल, उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार और अखिल भारत दस्तकारी मण्डल द्वारा वित्त प्रदान किया जा रहा है।

तेलंगाना में हैदराबाद स्थित औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड अपनी सबद्ध सहकारी समितियों के कार्यों के समन्वय तथा बेहतर वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए शिखर संगठन के रूप में कार्य करता आ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप चर्म शोधन, तेल, बड़ईगिरी तथा

लोहारी, हाथ धान कुटाई, ग्रामीण कुम्हारी और ईंट प्याई, हाथ कताई और बुनाई, हाथ कागज तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के कारीगरों ने अपनी औद्योगिक सहकारी समितियाँ गठित की हैं। इन सहकारी समितियों के कार्य संचालन में निम्नांकित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है (१) औद्योगिक सहकारिता के सिद्धान्तों और लाभों की समझ का अभाव, (२) वित्त काल में औद्योगिक सहकारी समितियों की असफलता, जिसके फलस्वरूप कारीगरों में ऐसी समितियाँ गठित करने का उत्साह कम हो गया है, (३) कानूनों और नियमों का, जिन्हें कारीगरों को समितियों के सदस्य की हैमियत में पालन करना पड़ता है, जटिल कार्यान्वय, (४) अधिक योग्यता प्राप्त तथा कार्यक्षम कार्यकर्त्तों का अभाव, क्योंकि वे औद्योगिक सहकारिता को अपने लिए लाभदायक नहीं पाते हैं, (५) वित्त प्रदान करने वाले अनेक अभिकरणों—जैसे सरकार, अखिल भारतीय मण्डलों तथा राज्य मण्डलों—द्वारा वित्त मंजूर करने में देर, जिसके कारण समितियों के सदस्यों में कुंठा व्याप्त हो जाती है, (६) सहकारी समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों की शिक्षा देने की सुविधाओं का अभाव, और (७) उत्पादनों की वित्तीय सुविधाओं की अपर्याप्तता।

इन विषयों पर गंभीरता से विचार करके उचित कदम उठाने चाहिये।

औद्योगिक सहकारिता के विकासार्थ सरकार की सशोधित नीति के परिणाम-स्वरूप लघु स्तरीय उद्योगों और ग्रामीण औद्योगीकरण के विकास में इस क्षेत्र के अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की आशा है। अधिकारियों का अनुमान है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ४०,०००, उनकी सदस्य-संख्या ३० लाख और अंश-पूँजी २० करोड़ रुपये हो जायेगी।

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) १९ सितम्बर १९६३

समग्र विकास कार्यक्रम

कोदण्डरामन वैद्यनाथन

ग्राम इकाई के निवासियों पर ग्राम इकाई कार्यक्रम के संचालन का क्या प्रभाव पड़ा है, इसे आकना आसान नहीं है, फिर भी, तीसरी पंचमाला योजना के अन्त में इस बात का एक मोटा-मोटी चित्र प्राप्त करना सम्भव हो सकता है कि किसी ग्राम इकाई में क्या परिवर्तन हुए हैं।

खादी और ग्रामोद्योगों के विकास सम्बन्धी अनुभव ने यह दिखा दिया है कि जब तक स्थानीय व्यक्ति (देश में ग्रामीण आबादी का विशाल बहुमत) इसे नहीं अपनाते, काम का विस्तार नहीं हो सकता। अनुभव से यह भी प्रतीत हुआ है कि कार्य का विस्तार होने, उत्पादन बढ़ने तथा सरकारी सहायता प्राप्त होने के बावजूद वह एक बन्द गली में ही फस गया अर्थात् प्रगति नहीं कर सका। इसलिए खादी और ग्रामोद्योग मूल्यांकन समितियों ने सुझाया कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को ऐसे चुनिन्दा क्षेत्रों में मधन प्रयास करने चाहिये, जहाँ वातावरण अनुकूल हो। इस प्रकार के क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों का लोक-आवश्यकताओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर आश्रित विकास करना चाहिये।

बहुविध लाभ

एक सुसंयोजित आधार पर कार्यक्रम को इस प्रकार कार्यान्वित करने के फलस्वरूप ग्रामीणों के लिए रोजगारी के अवसर बढ़ेंगे, उत्पादन में वृद्धि होगी (उत्पादन अधिकांशतः स्थानीय उपयोग के लिए होगा), गँवों से बाहर जानेवाला पैसा रोका जा सकेगा और क्षेत्र में पैदा हुए कृषि उत्पादनों को स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस प्रकार ग्रामीण अच्छा जीवन-स्तर बनाये रखने में समर्थ होंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकांश अभिक्रम और विनीय माधन-ओत ग्रामीणों के होंगे। पचासवें राज्य सस्थाओं को जिन्हे आज विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं, इस प्रकार की

योजनाओं में दिलचस्पी लेनी चाहिये। कार्यक्रम तभी सफल हो सकेगा।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

क्षेत्र के लोगों की वास्तविक आवश्यकताएँ जानने तथा विस्तारशील अर्थ-व्यवस्था—जोकि विभिन्न विकास योजनाएँ प्रारम्भ करने में चलाने से बन सकती हैं—के अनुसार कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर लोगों द्वारा उपयुक्त आयोजन करना आवश्यक है। यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि क्षेत्र में काम करनेवाले सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा गैर सरकारी यानी सभी रचनात्मक सगठनों का सहयोग प्राप्त हो। सामुदायिक विकास विभाग, सहकार विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग, सरकारी अभिकरण हैं, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, अखिल भारत हाथ करघा मण्डल, अखिल भारत दस्तकारी मण्डल, केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल, केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद, अर्ध-सरकारी अभिकरण हैं, और सर्व सेवा सच, गांधी स्मारक निधि, कस्तूरबा स्मारक निधि, अखिल भारत हरिजन सेवक सच, अखिल भारतीय आदिम जाति सेवक सच, भारत सेवक समाज आदि गैर-सरकारी अभिकरण हैं।

उक्त विभिन्न अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई अभियान चलाने से पूर्व कमीशन के अंतर्गत विभिन्न विभागों में परस्पर परिपूर्ण समझ और समन्वय होना चाहिये। इसलिए यह वाछनीय है कि जब ग्राम इकाइयों का चयन किया जाय तथा उन पर स्वीकृति दी जाय तो कमीशन के विभिन्न निर्देशालयों के क्षेत्रीय कर्मचारी उन क्षेत्रों के विकास पर इस प्रकार अपना ध्यान केन्द्रित करें कि उनकी सभी गतिविधियों से स्थानीय

लोगों में काम के लिए अभिक्रम और उत्साह का विकास हो। इसके लिए क्षेत्र के विकास के एक व्यापक चित्र का सामने रखना आवश्यक हो सकता है। यह काम उक्त विभिन्न अभिकरणों के सलाह-मशविरे में स्थानीय सगठनों को करना चाहिये।

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अभी दो ही वर्ष और हैं। इस योजना काल के अन्त में कमीशन के कार्यक्रम—ग्राम इकाई तथा अन्य कार्यक्रम—चलनेवाले क्षेत्रों के लोगों पर पड़े प्रभाव का कम से कम एक स्थूल चित्र तो सामने आना ही चाहिए।

यदि हम अपने प्रयासों को सघन रूप देकर कुछ विशेष सफलता प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं तो निश्चय

ही इसका देश में सामाजिक व आर्थिक दोनों ही दृष्टियों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि अब तक जिन इकाइयों का प्रवर्तन हुआ है तथा शेष दो वर्ष की अवधि में जिनका चयन-प्रवर्तन हो सकता है उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जाय, उनमें सुकाय किया जाय। जिन अन्य क्षेत्रों में पहले से ही विकास कार्य शुरू हो चुका है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाय, ताकि उन क्षेत्रों में भी, उन्हें समग्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से, अन्य ग्रामोद्योगों का काम प्रारम्भ करना सम्भव बन पड़े।

बम्बई १५ फरवरी १९६४

विश्व-जनसंख्या में प्रौढ़-साक्षरता का अनुमानित प्रातिशत्य १९५०

	पन्द्रह वर्ष और उससे ज्यादा उम्र की अनुमानित आबादी (दस लाख में)	प्रौढ़ साक्षरता का अनुमानित प्रातिशत्य
विश्व	१,५८७	५५-५७
अफ्रीका		
उत्तरी अफ्रीका	४०	१०-५७
उष्ण कटिबन्धीय और दक्षिणी	८०	१५-२०
अमेरिका		
उत्तरी अमेरिका	१२६	९६-९७
मध्य अमेरिका	३०	५८-६०
दक्षिण अमेरिका	६७	५६-५८
एशिया		
दक्षिण पश्चिम	३७	२०-२५
दक्षिण मध्य	२८७	१५-२०
दक्षिण पूर्व	१०२	३०-३५
पूर्व	४०४	५०-५५
यूरोप		
उत्तर और पश्चिम	१०२	९८-९९
मध्य	९६	९७-८७
दक्षिण	९५	७९-८०
सोवियत समाजवादी गणतंत्र सघ	११६	८९-९०
ओसेनिया	९	९०-९५

स्रोत 'यूनेस्को', १९५७, पृष्ठ १५।

आंध्र प्रदेश की दस्तकारियाँ

श्रीपति रंगनाथ

प्रस्तुत लेख में आंध्र प्रदेश में दस्तकारी उत्पादनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, उन पर चर्चा की गयी है।

भारतीय दस्तकारी उत्पादनों को अपनी सुन्दरता और उपयोगिता के कारण एक लम्बे समय से उच्च स्थान प्राप्त था। भूत काल में दस्तकारों ने, एक वर्ग के रूप में, व्यापारिक काम-धंधे के लिए अपने कौशल और हस्त-लाघव के प्रयोग की अपेक्षा अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और स्वान्त सुखाय श्रम का प्रदर्शन किया। वे अपने उत्पादनों के विशिष्ट तथा अनुपम आन्तरिक मूल्य से ही सन्तुष्ट रहे और अपने-आपको दूसरों की प्रशंसा का भागी बनाया। इस प्रकार के प्रशसनीय कार्य और उसके पीछे उत्सर्ग की भावना से निस्सन्देह कला के पारखियों की ओर से उन्होंने मान्यता प्राप्त की, लेकिन इससे दस्तकार वर्ग को कोई विशेष समृद्धि प्राप्त नहीं हुई।

चन्द चोटि के दस्तकार जिन्हे वशानुगत रूप से कला-कौशल और उसका रहस्य प्राप्त हुआ, व्यक्तिगत दस्तकारियों का काम करते थे। तत्कालीन शासकों और श्रेष्ठी वर्ग से, सामान्यतः उन्हें सहायता एवम् संरक्षण प्राप्त था। एकमुश्त भारी तादाद में उत्पादन होने लगने और धीरे-धीरे करके प्राचीन श्रेष्ठी वर्ग का लोप हो जाने के कारण आज उनके बुरे दिन आ गये हैं। इस प्रकार का विशिष्ट कौशल आज भी सुरक्षित रखा जा सकता है, बगर्ते कि दस्तकार अच्छी हालत में हों और जीविकोपार्जन के लिए केवल उमी पर निर्भर न रहें।

बेरोजगारी रोकने के लिए

हम भूतकालीन आत्मतुष्टि वाला रख रखना बर्दास्त नहीं कर सकते। दस्तकारियों को सामान्यतः लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमारी ग्रामीण अर्थ-

व्यवस्था—जिसका देश की ८२ प्रति शत आबादी से ताल्लुक है—का स्तर गुजर-बसर भर कर लेनेवाला है, जहाँ उपभोक्ता सामानों की आवश्यकता सीमान्त से भी नीची है। हमारी आबादी बढ़ रही है और उसके साथ ही बेकारों की संख्या। यह महसूस किया जाता है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के आस-पास के इलाकों में पूर्ण तथा अल्प बेरोजगारी फैलने देने को रोकने के लिए एक प्रभावशाली उपाय यह है कि मौजूदा दस्तकारियों का पुनरुद्धार कर उनमें प्राण फूँके जायें। वस्तुतः वे हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, क्योंकि एक तो उनमें ऊपरी खर्चों के लिए विशेष व्यय की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरे बाप से बेटे को वशानुगत कौशल की प्राप्ति होती रहती है। चूँकि उत्पादन के विभिन्न क्रमों का काम किसी परिवार के भिन्न-भिन्न व्यक्ति करते हैं, इसलिए उत्पादन खर्च अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इस लाभ की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि इन दस्तकारियों में थोड़ी-सी आधुनिक उत्पादकता का समावेश हो तो, ये मूल्य तथा गुण दोनों ही दृष्टियों से यंत्रों की सहायता से तैयार माल का मुकाबला कर सकती हैं।

दुर्भाग्य से बिक्री व्यवस्था का अभाव होने की वजह से दस्तकारियों के काम की गति धीमी पड़ जाती है तथा कच्ची सामग्री व उपलब्ध कौशल का प्रायः अल्पोपयोग होता है। किसी उद्योग की उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है, लेकिन अगर उसी हिसाब से उसकी बिक्री नहीं बढ़ती है तो उत्पादन-वृद्धि की कोई तुक नहीं रह जाती। बाजार अनुसंधान से केवल विक्रय क्षमता की मौजूदा

तथा माग के भौवी रख का सुझाव ही मिल सकता है। इसके लिए बिक्री-व्यवस्था सम्बन्धी प्रयासों का करना आवश्यक है।

अब हम आन्ध्र प्रदेश की दस्तकारी वस्तुओं की बिक्री-व्यवस्था पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आन्ध्र प्रदेश में अनेक दस्तकारियाँ प्रचलित हैं, जिनमें बिदरी काम, रजत जरदोजी काम, निर्मल काम, हिमरू, ऊनी कालीन तथा नमदे, काठ के खिलौने, चर्मोद्योगी सामान, मिट्टी की बनी वस्तुएँ, बेत और बास की चीजे, धातु के बर्तन, वाद्य-साज आदि शामिल हैं। अलग-अलग दस्तकारियों के बिक्री-सम्बन्धी पक्ष पर विचार करना अप्रासंगिक होगा। अतः उनमें से कुछ पर गुण-स्तर, अनुसंधान और डिजाइन, बिक्री-व्यवस्था तथा निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से सामान्य विचार करना ही पर्याप्त होगा।

आन्ध्र प्रदेश की दस्तकारियाँ

वारगल तथा एलूरू की कालीन और नमदा बुनाई आन्ध्र प्रदेश की एक प्राचीनतम दस्तकारी है। ये दो उद्योग करीब ५०० कारीगरों को पूर्ण और आंशिक रोजगारी प्रदान करते हैं। फिलहाल करीब १२,००,००० रुपये का सामान प्रति वर्ष पैदा होता है। इसमें एलूरू के कालीन उद्योग का हिस्सा दस लाख रुपये का है। इन उत्पादनों का उपभोग अधिकांशतः राज्य के बाहर होता है। अधिकांश माल निजी तौर पर बाहर भेजा जाता है तथा लगभग एक लाख रुपये का माल सरकारी बिक्री भवनो के जरिये बेचा जाता है। इस उद्योग में विदेशी विनिमय अर्जित करने की क्षमता की दृष्टि से सरकार इस दस्तकारी को काफी महत्व देती है और कारीगरों की पूँजीगत ऋण, उपकरण तथा प्राविधिक ज्ञान प्रदान करने के रूप में सहायता करती है। कारीगर अपना काम सुचारू रूप से कर सके इसके लिए अनुकूल अवस्थाएँ निर्मित करने की दृष्टि से सरकार ने एक सामूहिक सुविधा केन्द्र खोला है। एक ऊन प्रशोधन तथा रंगाई सयंत्र स्थापित करने की भी योजना है।

निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से न केवल हिमरू, बिदरी,

हाथी दात आदि के सम्बन्ध में बल्कि एलूरू और वारगल के कालीनों के लिए भी मानक निर्धारण योजना लागू की गयी है। फिलहाल ६ लाख ३९ हजार रुपये का मानक वाला माल है। मानक निर्धारण केन्द्रों को शक्तिशाली बनाने के लिए उपकरणों, तकनीकों, परीक्षणों, आदि के सम्बन्ध में सुधार किये जाते हैं।

कुछ दस्तकारियों के प्रतिरूप तैयार करने के लिए एक अनुसंधान और नमूना केन्द्र भी स्थापित किया गया है। इन नमूनों (डिजाइनों) से दस्तकारियों के परम्परागत प्रतिरूपों के पुनरुद्धार की, यदि आवश्यक हुआ तो सुधार की भी, और लोकप्रिय होने की अपेक्षा है तथा फलस्वरूप तिरुचनूर के खिलौने, बिदरी, हिमरू तथा निर्मल काम-वाले उत्पादनों की बिक्री बढ़ने की भी आशा है।

बिक्री व्यवस्था

विभिन्न और बहुविध किस्मों के होते हुए भी कठोर स्पर्धा के कारण आन्ध्र प्रदेश की दस्तकारियों के लिए एक नियमित व व्यापक मँग निर्मित करना मुश्किल हो रहा है। और फिर, सुनिश्चित तथा तैयार बाजार की कमी के कारण दस्तकारों को काफी लम्बे समय तक अपने उत्पादनों का स्टॉक रखना पड़ता है। बाजार प्राप्त करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन-स्रोत भी नहीं हैं। बताया जाता है कि कुछ एक मालों की कमी है तो दूसरी ओर जो हैं वे निम्न कोटि के हैं। विदेशी विनिमय की कमी होते हुए भी प्रायः दस्तकारों को निर्यात पर निर्भर रहना पड़ता है। अतएव उन्हें अपने अस्तित्व के लिए दस्तकारी सहकारों जैसी चन्द अन्य संगठित संस्थाओं पर निर्भर करना पड़ता है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में १५० से ज्यादा दस्तकारी सहकारी समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य-संख्या २०,००० थी। इन सहकारों के अन्तर्गत प्रायः राज्य की सभी दस्तकारियाँ आ जाती हैं। वर्ष १९६२-६३ के दौरान भाधवमाला के लाल लकड़ी के खिलौने बनाने का उद्योग, हैदराबाद के निकट अलवाल का मच सम्बन्धी उपकरण बनाने का उद्योग, चिराला का ठप्पा छपाई

और रगाई उद्योग आदि जैसे काम भी इनके अन्तर्गत ला पटके गये हैं।

सरकार' समितियों की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण-सह-अनुदान प्रदान करने और जब तक समितियाँ अपने पैरों पर खड़ी होने में समर्थ न हो जाये तब तक के लिए प्रबन्ध व प्रशामन सम्बन्धी सहायता देने के लिए इच्छुक हैं।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान ६ लाख ५० हजार रुपये और तीसरी पंचसाला योजना में ५ लाख रुपये दस्तकारी सहकारिताओं को ऋण तथा अनुदान स्वरूप वितरित किये गये। गत वर्ष बीस समितियों ने ७४,००० रुपये सहायता स्वरूप प्राप्त किये। इनके अन्तर्गत १६ दस्तकारियाँ थी। इसी प्रकार ४० अन्य सहकारी समितियों ने ५६,९०० रुपये के बराबर व्यवस्थापकीय सहायता प्राप्त की। समितियों को रुपये-पैसे और तकनीक सम्बन्धी यह सहायता मिलने से उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन १९६१-६२ में छ लाख रुपये का हुआ था और १९६२-६३ में ७ लाख ८१ हजार रुपये का।

बिक्री को बढ़ावा

बिक्री-व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से राज्य के खास-खास स्थानों में सात दस्तकारी भवन खोले गये हैं। इन भवनों में १९६२-६३ में कुल ११ लाख ५६ हजार रुपये की बिक्री हुई। राज्य के बाहर प्रमुख स्थानों में बिक्री भवन खोलने की योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। अपेक्षा की जाती है कि समय पाकर इनसे अन्तर्राज्यीय दस्तकारी व्यवसाय मजबूत बनेगा। राज्य दस्तकारी सलाहकार मण्डल की प्रमुख तीर्थ स्थानों, रेलवे स्टेशनों तथा भ्रमण सूचना केन्द्रों में नवीनतम दस्तकारी उत्पादनों का प्रचार करने और प्रदर्शन कक्ष स्थापित करने की योजना है। गत वर्ष बताया जाता है कि हैदराबाद भवन के दस्तकारी निर्यात विभाग ने १२,००० रुपये का माल 'ट्रायल आर्डर' के मुताबिक सीधे रूप में भेजा।

निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि में बाजार सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक अध्ययन, बाजार परीक्षण, बिक्री के उपाय, परिकल्पनात्मक तरीके, दृष्टिकोण निर्धारण तथा अन्य इसी प्रकार की वैज्ञानिक बिक्री योजनाओं का महत्व आसानी से समझ लिया जाता है, लेकिन कभी-कभी इनके निहितार्थ उतनी ही अच्छी तरह नहीं समझे जाते। ऐसा इसलिए नहीं है कि निर्यात प्रोत्साहन को गति प्रदान करने के लिए हमारे उद्यमियों अथवा सरकार में अभिन्न की कमी है, लेकिन इसलिए कि सभी प्रकार के व्योरे का ध्यान रखते हुए आवश्यक प्रारम्भिक कार्य के लिए इतने परिबध्य और प्राविधिक ज्ञान की जरूरत होती है कि वह सहकारों के बूते के बाहर की बात है।

ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारी दस्तकारियों की कीमत उचित हो, वे अच्छे गुण-स्तर की हो, उनकी डिजाइने कल्पनात्मक हो, आकर्षित ढंग से पैक की गयी हो, उनका प्रभावक वितरण तथा मुद्राचार हो तो निश्चय ही उन्हें बाजार की प्राप्ति होगी। तथापि, एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था में इतना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरत है उपभोक्ता प्राप्त करने के लिए अनवरत उस काम में जुटे रहने की। व्यापार मेलों, औद्योगिक प्रदर्शनियों, प्राल्यक्षिक कक्ष, फैशन प्रदर्शन, प्रकाशन, विज्ञापन आदि के जरिये प्रचार तथा अन्य इसी प्रकार की बातों से निस्सन्देह विदेशी ग्राहकों को हमारे उत्पादनों की जानकारी होती है, तथापि, वे हमें एक तुरन्त उपलब्ध बाजार की सुनिश्चितता नहीं प्रदान करते।

अन्तर्राष्ट्रीय शुल्क-पद्धति (टैरिफ), प्रशासनात्मक खामियों, व्यापारिक अवस्थाएँ, कार्य प्रणाली विषयक विलम्ब आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं जो निर्यात व्यापार में बाधक हैं। सरकार और निर्यात जोखिम बीमा निगम, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, औद्योगिक तथा व्यापारिक सघ, अन्वेषण सूचना केन्द्र व व्यापार सलाह केन्द्र आदि जैसी सम्बद्ध संस्थाओं से प्रभावशाली रूप में सहायता मिलने पर इन खामियों पर काबू पाया जा सकता है।

हैदराबाद, ७ नवम्बर १९६३

त्रिपुरा की अर्थ-व्यवस्था और खादी-ग्रामोद्योगों की सम्भावना

त्रिपुरा में कृषि-उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल क्षेत्र है। स्थानीय जन-जातियाँ हाथ कताई और हाथ बुनाई की कला से अच्छी तरह जानकार हैं। प्रशोधन तथा अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

त्रिपुरा एक भूतपूर्व रजवाड़ा है, जो १५ अक्टूबर १९४९ को भारतीय संघ में शामिल हुआ। त्रिपुरा की सीमा पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण में अनेक स्थानों पर पाकिस्तान से मिलती है। इसके उत्तर-पूर्व में असम राज्य है। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगभग ५२० मील और असम के साथ १८० मील की है।

इसका क्षेत्रफल ४,११६ वर्ग मील है। इसकी अधिकतम लम्बाई ११४ मील और अधिकतम चौड़ाई ७० मील है। कुल जंगल क्षेत्र ६,३५२ किलोमीटर है। यह चेरापूजी वृत्त में होने के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। यह क्षेत्र चक्रवात (तूफानी हवा) से प्रभावित माना गया है। बाढ़ तथा अन्य दैवी आपदाएँ विनाश के पहाड़ अपने साथ लाती हैं और एक भाग को दूसरे भाग में अलग कर देती हैं।

जन-संख्या और साक्षरता

त्रिपुरा की कुल जन-संख्या ११,४२,००५ है, जिसमें शहरी जन-संख्या १,०२,९९७ और ग्रामीण जन-संख्या १०,३९,००८ है। परिगणित जन-जातियों की आबादी ३,६०,०७० और परिगणित जातियों की १,१९,७२५ है।

राज्य में साक्षरता २०.२ प्रति शत और जन-संख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर १०७ है।

प्रशासनिक दृष्टि से त्रिपुरा १० उपखण्डों में विभाजित है, जिनमें ६ शहर और ५,२८६ गाँव हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण इस प्रकार है

उप-खण्ड	क्षेत्रफल (वर्ग मील में)	जन-संख्या
अमरपुर	५२७	५६,३६५
बेलोनिया	३९४	८४,८२७
धर्मनगर	६६२	१,२७,५४८
कैलाशहर	४६४	१,०४,१२६
कमलपुर	२४०	६१,६७५
खोवई	५३८	१,२९,९४८
सुब्रूम	२३८	४३,३९७
सरदार	६०२	३,६६,०७६
सोनमुरा	२०५	७७,९६९
उदयपुर	२४६	९०,०७४
	४,११६	११,४२,००५

त्रिपुरा को अनवरत शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्य सरकार के स्रोतों पर बहुत दबाव पड़ता है। राज्य तक पहुँचने के लिए स्थल-मार्ग का प्रायः अभाव होने के कारण वहाँ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, कलकत्ता से वहाँ की राजधानी अगरतला में वायुयान द्वारा सामान पहुँचा कर की जाती है।

कृषि की प्रधानता

यह क्षेत्र मुख्यतः कृषि-प्रधान होने के कारण कृषि-उद्योगों के विकास के लिए वहाँ अच्छा क्षेत्र पड़ा है अर्थात् वहाँ इनके विकास की बहुत गुंजाइश है। राज्य में

रेल की व्यवस्था या तो है ही नहीं या फिर बहुत ही कम। विद्युत पूर्ति भी बहुत दुर्लभ है। परिवहन की समस्या भी अत्यन्त जटिल है। एक मात्र स्थल-मार्ग है असम-अगर-तल्ला रोड। शक्ति और परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण वहाँ बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती। जन-संख्या का बड़ा हिस्सा शरणार्थियों तथा जन-जातियों का होने के कारण आवश्यकताएँ कम हैं और लोगों की क्रय-शक्ति भी कम है। राज्य को परमावश्यक कृषि वस्तुओं, वन्य उत्पादन, मवेशी और मुर्गी-पालन के सन्दर्भ में सोचना पड़ेगा। इस प्रकार राज- की परि-स्थितियाँ खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए अनुकूल हैं। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने त्रिपुरा को पर्वतीय एवम् सीमांत क्षेत्र योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया है और वहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोल रखा है। खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों के विकास की गुंजाइश कुछ इस प्रकार है

खादी

राज्य में खादी कार्यक्रम के लिए अच्छी गुंजाइश है। राज्य में खादी सूतकार और बुनकर हैं। आदिवासी स्वावलम्बन के आधार पर हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई करने में पटु हैं। राज्य में प्राप्त अनुकूल परिस्थितियों और राज्य के लोगों की रोजगार प्रदान करने की सर्वोपरि आवश्यकता के विचार से खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने वहाँ छ त्कुए के अम्बर चरखे की शुरुआत करने की योजना स्वीकृत की है।

बेलोनिया शहर और निहारनगर में छ त्कुएवाले अम्बर चरखे के केन्द्र हैं। निहारनगर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। यह समझा गया कि वहाँ खादी और ग्रामोद्योग बहुत सफलता पूर्वक विकसित किये जा सकते हैं। उक्त क्षेत्र शरणार्थी बस्ती है। वहाँ पर पुनर्स्थापित शरणार्थियों के अलावा जन-जातियों के लोग भी हैं। उक्त क्षेत्र के लोग ऐसी अवस्था में हैं कि खादी और ग्रामोद्योगों के कार्य से उन्हें बहुत राहत मिलेगी। क्षेत्र में बुनाई की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। केन्द्र जन जाति-प्रधान क्षेत्र के

समीप है और इससे उन्हें छ त्कुए के अम्बर चरखे पर हाथ कटाई करने का प्रोत्साहन मिलेगा। यह क्षेत्र हाथ धान कुटाई उद्योग के विकास के लिए भी अनुकूल है। ग्रामीण तेल उद्योग के विकास के लिए अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

आगरतल्ला जेल में

आगरतल्ला स्थित केन्द्रीय जेल में एक और केन्द्र है। जेल अधिकारी अपने बुनाई विभाग में हाथ कते सूत का प्रशोधन करने के लिए तैयार हैं और आगे चल कर मिल सूत के बदले हाथ कते सूत का व्यवहार करना सम्भव हो सकेगा। हाथ धान कुटाई, ग्रामीण तेल, बढईगीरी, मधुमक्खी-पालन, मुर्गी-पालन, मत्स्य-पालन, टोकरी बनाना, कृषिक तथा उद्यान सबधी कार्य और खादी जैसे अनेक उद्योगों का काम उक्त जेल में चलता है।

चौथा केन्द्र आगरतल्ला से १३ मील दूर पर बरजोलाई जीरानिया खण्ड में स्थित 'सर्वोदय कर्म मन्दिर' में चलता है। गांधी ग्राम विकास समिति अपने 'सर्वोदय कर्म मन्दिर' में अनेक सर्वोदय प्रवृत्तियाँ चलती हैं। यह मुख्यतः जन-जाति क्षेत्र है, जहाँ पर बुनाई आदि जन-जातियों के अपने तरीके से प्रचलित है। समिति बाल मन्दिर, निशुल्क औषधालय और ग्रामीण तेल तथा खादी जैसे ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का संचालन भी करती है। हाल ही में प्रशिक्षण के लिए उम्मेदवारों का चुनाव किया गया है, जिनमें स्त्रियाँ भी सम्मिलित की गयी हैं।

पहली किस्त के रूप में चरखे और तकनीकल कर्मचारी राज्य के बाहर के व्यक्ति थे। यह जरूरी है कि स्थानीय कार्यकर्त्ता प्रशिक्षित तथा तैयार किये जाय और चरखों तथा अन्य उप-साधनों का भी स्थानीय तौर पर उत्पादन किया जाय। भावी कार्यक्रम की दृष्टि से ये दोनों अत्यधिक आवश्यक हैं।

त्रिपुरा में अन्य अनेक ग्रामोद्योगों के विकास की असीमित शक्यताएँ हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है।

त्रिपुरा मुख्यतः चावल उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें ४,४५,५०० एकड़ भूमि पर धान की खेती होती है और धान की कुल उत्पत्ति १,७०,७५० टन वार्षिक है। हाथ धान कुटाई उद्योग वहाँ का एक परम्परागत कुटीर और ग्रामोद्योग है। गाँवों में हर घर में परम्परागत ढेकी मिलती है। गाँवों में प्रत्येक घर में धान उसना करने और उसकी कुटाई करने का काम भी होता है। इस क्षेत्र में लोगों का प्रधान भोजन चावल है तथा इसके फलस्वरूप इस उद्योग की असीमित शक्यताएँ हैं। इस उद्योग के अन्तर्गत काम शुरू करने के लिए कुछ क्षेत्रों का विशिष्ट रूप से सर्वेक्षण किया गया है।

ग्रामीण तेल

राज्य में तिलहनो में मुख्यतः सरसो, अलसी और तिल पैदा होता है। स्थानीय तौर पर उपभोग में लाया जानेवाला तेल सरसो के बीजों से निकाला जाता है। तिलहन पैदा करनेवाला क्षेत्र १९,१०० एकड़ और कुल उत्पादन २,८४० टन वार्षिक है।

रेशा

त्रिपुरा में १,७५,००० गाठ पटसन का उत्पादन होता है और पटसन की खेती के अन्तर्गत (मेस्ता सहित) ६४,००० एकड़ भूमि है। त्रिपुरा में अनन्नास बहुतायत में होता है और अभी अनन्नास के रेशे का कोई उपयोग नहीं होता। फल निकल आने के बाद रेशा बेकार ही जाता है। पता चला है कि दक्षिण कनारा के नुदङ्गिद्री स्थान पर इस रेशे के सम्बन्ध में शोध की गयी और उसके परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे। त्रिपुरा में केले

के रेशे बहुतायत में हैं। वहाँ पर वण्य केले भी पैदा होते हैं और इस केले का डण्ठल रेशा निकालने के लिए बहुत उपयोगी होता है।

चर्मोद्योग

त्रिपुरा में सात लाख मवेशी हैं और इसमें चर्मोद्योग के विकास का सभाव्य क्षेत्र है। छोटी-बड़ी खालों के बाजार का नियंत्रण कुछ दलालों के हाथों में है, जोकि उनका राज्य के बाहर निर्यात करते हैं। निर्मित वस्तुओं का आयात होता है। खाल के मामले में स्थानीय एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए तौर-तरीके खोजने पड़ेंगे, ताकि वैयक्तिक चर्म कार्य करनेवाले को खाल और चमड़े की बेहतर कीमत मिले तथा खालों का राज्य में ही शोधन तथा उपभोग हो सके, क्योंकि इसका राज्य से बाहर निर्यात करना न तो भित्तव्ययी है और न उसमें लाभदायक मूल्य ही प्राप्त होता है। सरकार को स्थानीय उत्पादन और उसके उपभोग के लिए आवश्यक सरक्षण प्रदान करके, इस उद्योग की सहायता करनी पड़ सकती है।

गन्ने की खेती के अन्तर्गत ७,२०० एकड़ भूमि है और उसका उत्पादन ९,००० टन वार्षिक है। गुड़-उत्पादन के विकास के लिए राज्य में अच्छी सभावना है।

राज्य में जिस दूसरे उद्योग के विकास की अपार सभावना है वह है मधुमक्खी-पालन। मधु-पेटी के सुव्यवस्थित निर्माण और पूर्ति तथा मधुमक्खी-पालकों द्वारा मधु संग्रह और उसकी बिक्री के सुनियोजित प्रयास करने के परिणाम-स्वरूप वैयक्तिक मधुमक्खी-पालकों एचम् साथ ही साथ राज्य की आय बढ़ायी जा सकेगी।

आगरतल्ला २४ जनवरी १९६४

पुस्तक समीक्षा

व्यापाराश्रम्बन्धी व्याख्याने : न्यायाधीश माधव गोविंद रानडे के अभिभाषण (१८७२-७३), प्रकाशक गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पूना, १९६३, पृष्ठ संख्या बाईस+ ६८, मूल्य . २५० रुपये ।

प्रस्तुत पुस्तिका में विगत शताब्दी के सुप्रसिद्ध समाज-सेवी न्यायाधीश माधव गोविंद रानडे के दो अभिभाषणों को, जो पूना में ८ दिसम्बर १८७२ और २२ फरवरी १८७३ को दिये गये थे, पुनर्मुद्रित किया गया है। उन दिनों उनकी उम्र महज ३० वर्ष की थी। फिर भी देश की आर्थिक समृद्धि से ताल्लुक रखनेवाली बातों की उन्होंने जिस सूक्ष्मता से व्याख्या की थी, वह विशेष महत्व रखती है। भारतीय जनता की दरिद्रता के लिए उन्होंने (१) विदेशी सत्ता के आधीन होने की वजह से भारतीय साधनों का भारी रिसाव तथा (२) दस्तकारी और कारखानों के विकास के लिए साधन-स्रोतों की कमी को जिम्मेवार बताया था। आज से लगभग ९० वर्ष पहले अपने देशवासियों को सोने और चाँदी के गहनों के रूप में कीमती पंजीगत साधनों को अनुत्पादक बना कर जिस ताला-कुन्जी में बन्द रखने के लिए उन्होंने फटकार बतायी थी, वही स्थिति आज तक बनी हुई है।

विदेशी सत्ता १५ करोड़ की आबादी से ५० करोड़ रुपये वसूल करती थी। और यद्यपि उन दिनों देशी

राज्यों में कर अदायगी की दर अंग्रेजी भारत से अधिक थी, लेकिन अंग्रेजी भारत से इंग्लैण्ड की ओर जानेवाली सम्पत्ति की मात्रा इतनी अधिक थी कि यहाँ की जनता का नुकसान अन्य क्षेत्रों के बजाय सबसे अधिक था। सात हजार यूरोपीयनों, ६० हजार यूरोपीयन फौजी सिपाहियों तथा पाँच हजार छोटे-बड़े नागरिक अफसरो पर ५३ करोड़ रुपये के व्यय के अतिरिक्त १० १/२ करोड़ रुपये भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को भेजती थी।

वाणिज्य और व्यवसाय की मात्रा में अभिवृद्धि के बावजूद इस व्याधि के मूल कारणों की ओर खास इशारा करते हुए न्यायाधीश रानडे ने कहा था— “कच्चे मालों” का इंग्लैण्ड की ओर निर्यात और तैयार मालों का आयात स्थानीय आबादी को, उसके जीविकोपार्जन के दायरे में वचित करता जा रहा है।”

युद्ध जैसी असामान्य स्थितियों में मालों की कमी की पूर्ति के लिए जब कभी इस देश से माँग की गयी तो उन अवसरों पर साबित हो गया कि भारत के बने माल अपनी श्रेष्ठता में अन्य देशों से कम नहीं हैं। उदाहरणार्थ श्रीमिया के युद्ध (१८५४) में भारत ने इंग्लैण्ड को सतोषजनक मालों की पूर्ति की, जबकि वही माल इंग्लैण्ड तब तक अन्य देशों से खरीद रहा था। दर असल, भारत का माल इतना पसन्द किया गया कि युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी हम से आयात होनेवाले मालों की टक्कर में भारतीय माल मँगाये जाते रहे।

उदाहरणार्थ, १८५१ से १८५५ के बीच ४३ लाख रुपये की चाय भारत से बाहर भेजी गयी। अगले ५ वर्षों में यह मात्रा ८३ लाख रुपये तक तथा उसके बाद के ५ वर्षों में २२३ लाख रुपये तक पहुँच गयी। कॉफी के मामले में भी सालाना निर्यात १८५०-५५ में ९३ लाख रुपये से बढ़ कर १८५५-६० में १३३ लाख रुपये तक पहुँचा। अगले ५ वर्षों की अवधि में यह निर्यात ५५३ लाख रुपये का हुआ।

इसी तरह अमरीकी गृह युद्ध का प्रभाव रूई के निर्यात पर पड़ा। १८६०-६८ में वह ४,२२,००० गॉठों से बढ़ कर १३,७०,००० गॉठ प्रति वर्ष तक पहुँच गया, जबकि अमरीका से इंग्लैण्ड आनेवाली २८,३८,००० गॉठों की औसत घट कर १३,५०,००० गॉठों तक हो गयी। उसके बाद के दिनों में भी भारतीय रूई का निर्यात कम नहीं हुआ। दर असल, १८७१-७२ में भारत ने अमरीकी गृह-युद्ध से पहले से अधिक रूई का निर्यात किया। इसके अतिरिक्त कई तरह के व्यवसायों का विस्तार होता गया—ऊन का कारोबार दूना हो गया। कपास की खेती में वृद्धि का अन्य नकदी फसलों पर गलत प्रभाव पड़ा।

अपने अभिभाषणों में रानडे ने बताया कि आयात-निर्यात प्रायः त्रिगुना हो गया है, चाय, चावल अफीम, कॉफी, रूई, ऊन आदि उत्पादनों का निर्यात बढ़ गया है। किन्तु रेशमी और सूती वस्त्र, शाल, चीनी आदि के निर्यात को नुकसान पहुँचा है।

श्री रानडे ने कहा कि महज व्यापार की अभिवृद्धि राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि को परिलक्षित नहीं करती। उसमें इस बात को देखना है कि आयात किये जा रहे माल देश में पैदा होते हैं या नहीं और उस आयात से देशी उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलायत से आयात किये जा रहे माल ऐसे हैं, जो देशी कारीगरों द्वारा तैयार किये जाते रहे हैं, जिसका भ्रान्तक प्रभाव देशी उद्योगों पर पड़ता है।

गैर कृपि धंधों की बन्दी के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हुए श्री रानडे ने कहा कि भारत में उत्पादित कच्चे

मालों को विलायत भेजा जाता है और उनसे तैयार माल बना कर पुनः भारत भेजा जाता है। भारत को पूर्णतः कृपि पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया गया, जिससे होनेवाली प्राप्ति, अन्ततः लुप्त-सी होती जा रही है।

औद्योगीकरण से जीवन-यापन का स्तर, जनता की शिक्षा तथा सस्कृति का स्तर ऊपर उठेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी औद्योगिक कार्यों में सलग्न लोगों में अधिक जागृति होती है। वे अन्याय का विरोध करने में समर्थ होते हैं या कम से कम अपनी आवाज बुलन्द करते हैं। विदेशी सत्ता के आधीन पड़े इस देश में इस स्थिति से मदद मिलती।

अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए शासक देश पर भारत की निर्भरता का जिक्र करते हुए रानडे ने कहा कि आर्थिक तौर पर भी यह देश उतना ही कमजोर हो गया है जितना राजनीतिक तौर पर। ऐसी गुलामी की जिन्दगी, जिसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम नहीं मिले, पहले दर्ज की बेवकूफी है।

रानडे की सारी बातें, हो सकती हैं, आज हमें मान्य न हों, लेकिन वे बातें उस पीढ़ी की चिन्तनधारा पर प्रकाश डालती हैं और यह बताती हैं कि उस जमाने के नेतागण उच्च वित्तीय मामलों में अपने देशवासियों को किस रूप से शिक्षित करना चाहते थे।

उन दिनों भी रानडे ने अभिभाषण मराठी में दिये थे, जब कि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट जैसे शब्दों के भी पर्यायवाची शब्द उपलब्ध नहीं थे। इस तथ्य से उन लोगों की आँखें खुल जानी चाहिये जो आज भी यह कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती।

इस तरह अप्राप्य अभिभाषणों को उपलब्ध कराने के लिए गोखले इन्स्टीट्यूट आफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनॉमिक्स धन्यवाद की पात्र है।

प्रोफेसर एन वी. सोवनी ने पुस्तिका में अपनी २२ पृष्ठों की भूमिका जोड़ कर उसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी है। उन्होंने उसमें यह बताने की कोशिश की है कि समय के साथ किस तरह इस तरह की विचार-धाराओं में परिमार्जन होता गया।

—प्रभाकर

रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन : लेखक वी ए वासुदेवराजू, स्वयम् लेखक द्वारा प्रकाशित, विस्तार अधिकारी (उद्योग) खादी-ग्रामोद्योग विद्यालय, गांधी निकेतन आश्रम, टी कल्लूपट्टी, मदुराई, १९६३ पृष्ठ संख्या १०५, मूल्य १ रुपया।

प्रस्तुत पुस्तिका में लेखक ने दो सवाल उठाये हैं—ग्रामीण औद्योगीकरण का सम्बोध और उसकी समस्याएँ। प्रथम की व्याख्या में लेखक ने ग्राम्यवादिता के गांधीवादी सम्बोध पर डाक्टर जे सी कुमारप्पा तथा जयप्रकाश नारायण जैसे सज्जनों की अभिव्यक्तियों से बहुत कुछ लेने की कोशिश की है। अर्थशास्त्रीय शब्दावली में इसका अर्थ है 'सक्षम उत्पादन,' 'सही वितरण' और 'आराम की ओर उन्मुख उत्पादन से पहले आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन।' और, 'स्थानीय साधन-स्रोतों तथा आवश्यकताओं के आधार पर देश के समूचे देहाती क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विस्तार करने' के जरिये उक्त काम में सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति तथा प्रविधि के उपयोग के सम्बन्ध में किसी को सिद्धान्त-वादी अथवा भावुक नहीं होना चाहिये। तब लेखक प्राणवान ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सम्बोध के सन्दर्भ में नौ प्रमुख ग्राम और लघु उद्योगों की सूची पेश करते हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त कोई पूछ सकता है कि जिस प्रकार के ग्रामीण औद्योगीकरण की लेखक कल्पना करता है क्या उससे हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उस संप्राण तत्व का समावेश हो सकेगा कि वह 'स्व-सृजन' और 'आत्म-निर्भर' बन जाय। 'स्व-सृजन और 'आत्म-निर्भर' ऐसे सम्बोध हैं जो अन्तर्विभागीय सम्बन्ध

दशति है। अतएव वे समग्र अर्थ-व्यवस्था में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की गतिशील शक्तियाँ कृषि की तकनीकों में क्रान्ति लाने पर निर्भर करती हैं।

समूची समस्या पर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से विचार करने पर कोई भी ग्राम और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक एकता का महत्व महसूस करेगा। किन्तु समुचित समग्रता के लिए हमें अपने कृषि क्षेत्र के सामाजिक विवरण की आवश्यकता है, जो दर असल, एक ऐसे अर्थशास्त्री का काम है जो हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सही संचालन के सम्पर्क में हो। ग्रामीण औद्योगीकरण की समस्याओं का लेखक ने जो सुन्दर वर्गीकरण किया है उसके बावजूद मेरी दृष्टि से यह अच्छा रहता कि वे अपने प्रशिक्षार्थियों को ग्राम के सामाजिक विवरण का प्रत्यक्ष ज्ञान करवाने की कोशिश करते। इस प्रकार के अनुभव-सिद्ध अध्ययन के अभाव में कोई भी यह महसूस करेगा कि ग्रामीण औद्योगीकरण का सम्बोध निर्बल पड़ जाता है।

— गो. श. रायचौधरी

हैडबुक ऑफ कॉमर्सियल इन्फार्मेशन :

अक-१, प्रकाशक वाणिज्य अनुसंधान तथा सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार, कलकत्ता, १९६४, पृष्ठ संख्या छ+४६६+३, मूल्य ११ रुपये।

लगभग २६ वर्षों तक बन्द रहने के बाद हैडबुक ऑफ कॉमर्सियल इन्फार्मेशन के पुनः प्रकाशन का स्वागत है। निर्यात प्रयासों में इसकी उपयोगिता के साथ-साथ इसकी आवश्यकता उन समस्त लोगों को पड़ेगी, जो देश के आर्थिक विकास में दिलचस्पी रखते हैं।

प्रकाशन का अंतिम अंक २६ वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। तब से अब तक की अवधि के परिवर्तनों के प्रतीक स्वरूप समूचे अंक में इरीनियरिंग उद्योगों के विवरण प्रस्तुत किये गये हैं तथा १०३ विभिन्न उत्पादनों का जिक्र किया गया है। उत्पादन, कच्चा माल, मूल्य, आयात, निर्यात, योजना के लक्ष्य आदि शीर्षकों से प्रत्येक उत्पादन के बारे में आम सूचनाएँ दी गयी हैं। प्रकाशन के अगले अंकों में वस्त्र तथा अन्य उत्पादित वस्तुएँ, खाद्य तथा अन्य कृषिक उत्पादन एवम् खनिज के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

इस प्रकाशन की एक विशेषता यह है कि डायरेक्टर जनरल श्री एम. मुब्रहमण्यन् ने इसकी भूमिका लिखी है और उसके सम्पादन कार्य में लगे समस्त अफसरों के नामों के साथ-साथ समस्त सहयोगियों, स्टैनो ग्राफरों, प्रूफ रीडरों तथा कार्य से सम्बन्धित अन्य लोगों के नाम भी उसमें प्रकाशित किये गये हैं।

आदिवासी सख्या ३, १९६३-६४, प्रकाशक आदिवासी अनुसंधान केन्द्र, उड़ीसा, सम्पादक जी एन दास, पृष्ठ सख्या १८२।

उड़ीसा के आदिवासी अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रकाशित **आदिवासी**, देश में आदिवासियों के सम्बन्ध में प्राप्त साहित्य में समृद्ध करता है। श्री उ. न. देवर् की अध्यक्षता में गठित अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जन-जाति आयोग के प्रतिवेदन ने आधुनिक भारतीय समाज में आदिवासियों की भूमिका के सम्बन्ध में नयी चेतना तथा आदिवासियों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त

करने के लिए देश के बौद्धिक वर्ग में नयी दिलचस्पी पैदा की है। **आदिवासी** का प्रस्तुत अंक एक विशेषांक है, जिसके विविध लेखों में उड़ीसा में आदिवासियों के सम्बन्ध में बुनियादी आकड़े पेश किये गये हैं, कमजोर वर्गों के बीच खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए इस अंक के आकड़े खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं के लिए विशेष उपयोग के होंगे। आदिवासी जीवन से सम्बन्धित अनेक चित्रों ने अंक का मूल्य और बढ़ा दिया है। ये चित्र हमें यह भी बताते हैं कि आदिवासी समाज आधुनिक औद्योगिक समाज से कितनी दूर है और उन्हें आधुनिक समाज में लाने के लिए हमें कितना काम करना है।

किसी खास विषय पर उस तरह की विशेष पत्रिका का प्रकाशन करना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए सम्पादक महोदय अपने श्रम के लिए बर्बाद के पात्र हैं। अंक की मजबूत, छपाई-मफाई काफी सुन्दर है। ऐसी पत्रिकाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। किन्तु इस सबके बावजूद प्रकाशन की कुछ त्रुटियों की ओर इशारा किये बिना हम नहीं रह सकते। समूचे अंक में वही इस बात का जिक्र नहीं है कि पत्रिका मासिक है, त्रैमासिक है या सार्वजनिक है, कहीं मूल्य नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि अंक पर १९६३-६४ का दूसरा अंक छपा है, किन्तु प्रकाशन की तारीख १४ नवम्बर १९६३ दी गयी है। यदि यह पत्रिका है तब फिर उसका प्रकाशन किसी एक विशेष दिन को होना चाहिये। और फिर, इस प्रकार के प्रकाशन को अपने गुण-स्तर यानी प्रकाशन सामग्री के बल पर आगे बढ़ने देना चाहिये।

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए 'ग्रामोद्योग' इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ से प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल एमोनिपेटेड एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ९०५, तारदेव, आर्थर रोड, बम्बई-३४। वार्षिक शुल्क २ ९० रुपये, एक प्रति २९ नये पैसे।

दशम वर्ष • मई १९६४ • अष्टम अंक



	पृष्ठ
ग्रामीण औद्योगीकरण में समस्याएं	-वैकुण्ठ ल. मेहता ५१९
वर्धा घानी से तेल सम्प्राप्ति	-राम कृ. श्रीवास्तव और माधव रा. देशपाण्डे ५२४
विकेन्द्रित कनाई और ग्रामीण रोजगारी	-केशव ग. देवधर और सौमित्र दे. नाडकर्णी ५२७
उत्तर प्रदेश में गुड की सहकारी विक्रय-व्यवस्था	-भारत भूषण कंशाल ५३१
मैसूर में ग्राम्य जन-शक्ति परियोजनाएँ	-स. म. वीरराघवाचार ५३७
बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में वानस्पतिक सम्पत्ति	-सुधाशु कुमार जैन ५४१
सूक्ष्म प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान	-भारतानन्द ५४६
चीनी का स्रोत ताड	-प्रकाश चन्द्र वासनीय ५५३
पचायत राज	-पुरुषोत्तम प्रभाकर ५५९
बैलों की आँतों का निर्यात व्यापार	-पोन्नूशामी कुण्डु राव ५६३
मुंशिदाबाद का हाथी दात शिल्प	-कमल बनर्जी ५६५
भारत में तिलहन पेरई उद्योग	-तरलोचन सिंह ५७०
विचार-विमर्श	
गरीब देश, आर्थिक विकास और समाज कल्याण	-जे. सु. तिरुवेक्कटाचारी ५७४
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और महिलाएँ	-सत्या कुमारी ५७६
धान की हाथ कुटाई व सेलीकरण	-तो मी सुन्दरम ५७९

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोदय', इर्ला, बम्बई-९६ से मुद्रित और प्रकाशित। छापी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थशास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विठ्ठे पार्ले (पश्चिम), बम्बई-९६ (ए एस) के पते पर भेजें। टेलीफोन नं. ५७१३२९।

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क ० ५० रुपये, एक प्रति २५ नये पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिये असिस्टेण्ट

इस अंक के लेखक

वैकुण्ठ लल्लूभाई मेहता
राम कृष्ण श्रीवास्तव
साधव राजाराम देशपाण्डे
केशव गणेश देवघर
सौमित्र देवीदास नाडकर्णी
भारत भूषण कमाल
सरगुर मदभूषणम बीरराघवाचार
सुधांशु कुमार जैन
भारतानन्द (मॉरिस फ़िडमन)
प्रकाश चन्द्र वासनीय
पुरुषोत्तम प्रभाकर
पोन्नूसामी कुप्पु राव
कमल बनर्जी
तरलोचन सिंह
नेडुमरम सुन्दरराजय्यगार
तिरुवैकटाचारी
सत्या कुमारी
तोबल मीनाक्षी सुन्दरम

—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य।
—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसन्धानशाला के कार्यभारी निर्देशक।
—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसन्धानशाला में सहायक।
—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में सूत उत्पादन निर्देशक।
—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसन्धानशाला में कनिष्ठ यांत्रिक अभियंता।
—गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के एम एम एच कॉलेज में वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष।
—मैसूर स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के 'पोस्ट ग्रेज्युएट रटडीज एण्ड रिसर्च इन इकनॉमिक्स' विभाग में अर्थशास्त्र के लेक्चरर।
—ब्रॉटनीकल सर्वे ऑफ इण्डिया की कलकत्ता स्थित सेण्ट्रल बोटनीकल प्रयोगशाला में इकनॉमिक बोटनीस्ट।
—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अवैतनिक सलाहकार (इजीनियरिंग)।
—इन्दौर स्थित सहकारी समितियों के पजीयक के कार्यालय में राज्य ताड-गुड सगठक।
—नयी दिल्ली स्थित 'इण्डियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज' में गवेषणा छात्र।
—मद्रास में हरिजन कल्याण कार्य में सलग्न सामाजिक कार्यकर्ता।
—खगरा (पश्चिम बंगाल) से प्रकाशित मुर्शिदाबाद समाचार के सम्पादक।
—योजना आयोग (नयी दिल्ली) की ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति में आर्थिक अनुसन्धानकर्ता।
—मद्रास विश्वविद्यालय के 'एग्रीकल्चरल इकनॉमिक रिसर्च सेण्टर' में जूनियर रिसर्च इन्वेस्टीगेटर।
—महिला तथा बाल कल्याण सम्बन्धी समस्याओं पर लिखती हैं।
—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के त्रिवेन्द्रम स्थित हाथ धान कुटाई उद्योग के सहायक विकास अधिकारी।

ग्रामीण औद्योगिकरण में समस्याएँ

वैकुण्ठ ल. मेहता

ऐसे चुनिन्दा क्षेत्रों में जहाँ मार्गदर्शी परियोजनाएँ चालू की गयी हैं सर्वेक्षकों के विशेष दलों द्वारा किये गये प्राविधिक-कार्थिक सर्वेक्षणों से सम्बद्ध क्षेत्र में कच्ची सामग्री के साधन-स्रोतों की उपलब्धि, उनके उपयोग की गुंजाइश, कृषि की अवस्था, विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए सस्थात्मक व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में जानकारी मिलनी है। बिहार के गया जिले में नवादा ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्र में ऐसा एक सर्वेक्षण किया गया। प्रस्तुत लेख में सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

दो वर्ष पूर्व ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति का गठन हुआ। देश के भिन्न-भिन्न भागों में ४०-५० ऐसे केन्द्रों का चयन करना इसका प्राथमिक कार्य था कि वहाँ ग्राम्य औद्योगिक विकास के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारम्भ किया जा सके। यह तय किया गया कि एक चुनिन्दा केन्द्र के अन्तर्गत तीन या चार सामुदायिक विकास खण्ड होंगे और वहाँ पर विकास योजना बनाने से पूर्व सर्वेक्षकों के विशेष दलों द्वारा प्राविधिकार्थिक सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण की रूपरेखा क्या होगी, इसका निर्णय किया गया और सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की गयी।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनों से एक व्यापक व सघन ग्राम्य औद्योगिक विकास कार्यक्रम में अभिरुचि रखनेवाले सभी व्यक्तियों को परिपूर्ण जानकारी मिलनी चाहिये। यदि सभी प्रतिवेदन आलोच्य प्रतिवेदन* की तरह सुस्पष्ट और विस्तृत तथा व्यापक हैं तो वे उद्योगों की विकास योजनाओं के लिए प्रशंसनीय आधार प्रदान करते हैं, जिनका प्रधान उद्देश्य है यथा सम्भव स्थानीय कच्ची सामग्री व अन्य साधन-स्रोतों का उपयोग करते हुए, प्रधानतः स्थानीय उपभोग की आवश्यकताओं के अनुसार

उत्पादन करते हुए और ऐसा करने के दौरान ग्राम समाज के सभी वर्गों के लिए, पूर्ण अथवा अश-कालीन, अनुरूप काम-धंधे ढूँढ निकालते हुए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को पहचानना। यह परियोजना क्षेत्र सम्भवतः अन्य चुनिन्दा क्षेत्रों के समान ही है। सामाजिक अवस्थाएँ क्षेत्र-क्षेत्र की भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। लेकिन समानता इस तथ्य में निहित है कि प्रत्येक क्षेत्र में मानव तथा सामग्री सम्बन्धी अछूते स्रोत हैं अर्थात् अभी तक उनका उपयोग नहीं हुआ है, यत्र-तत्र कृषि क्षेत्र में हुई कुछ प्रगति के बावजूद अर्थ-व्यवस्था निष्क्रिय है तथा यह कि इन कारणों से गरीबी की अवस्थाएँ बनी हुई हैं।

परियोजना क्षेत्र

परियोजना क्षेत्र में ३४१ गाँव हैं। आबादी ३ लाख २९ हजार है। औसत आबादी घनत्व प्रायः उच्च (प्रति वर्ग मील ८३०) है। प्रधान पेशा खेती है। कुल आबादी के ८१-४ प्रतिशत लोगों के जीविकोपार्जन का प्रधान साधन यही है। यह एक ऐसा प्रातिशत्य है जो प्रायः समूचे देश के प्रातिशत्य के समान ही है। कृषि के अलावा अन्य प्रकार के उत्पादन कार्य से ७ प्रतिशत को, व्यापार, वाणिज्य तथा परिवहन से ६२ प्रतिशत को और अन्याय्य सेवाओं से ५४ प्रतिशत को रोजगारी मिलती है। बेरोजगारी का अनुमान पुरुषों में चार प्रतिशत और महिलाओं में सात प्रतिशत होने

* ग्रामीण उद्योग परियोजना, नवादा (गया) गया जिले (बिहार) के नवादा, वारसली गज, कौआकोल और पकरो-बरवा सामुदायिक विकास खण्डों के प्राविधिकार्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिवेदन।

का है। ऐसा बताया गया है कि मजदूरों को साल में १६७ दिन का काम खेती में मिल जाता है और ३३ दिन का काम गैर-खेतिहर (निर्माण कार्यों में लगे कामगारों सहित) धंधों में। अल्प-बेरोजगारी पुरुषों में ३० प्रति शत और महिलाओं में ४८ प्रति शत होने का अनुमान है। जहाँ खेतिहर कर्मियों में यह अल्प बेरोजगारी अपेक्षाकृत खाली मौसम में रहती है, वहाँ कुम्हार, बाँस काम करने-वालों तथा ईंट-पथारों में यह उस वक्त रहती है, जबकि खेती-बाड़ी के काम में दम भर का भी अवकाश नहीं रहता। ऐसे वक्त वे प्रायः निष्क्रिय रहते हैं।

भूमि उपयोग पद्धति से भी सामान्य बातें सामने आती हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि बहुत ही कम (०.४८ एकड़) है। स्थूल अनुमान से ऐसा लगता है कि १८ प्रति शत परिवार भूमिहीन हैं। अधिकांश लोगों के खेत बहुत छोटे-छोटे हैं। केवल ४५ प्रति शत परिवार ही ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उनके खेतों का आकार आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है। नकद फसलों के अन्तर्गत खेतों का क्षेत्रफल बहुत मामूली है। तथापि, सिचाई के अन्तर्गत अच्छी खासी भूमि आती है। कुल १,५८,४८८ एकड़ कृष्य भूमि में से १,२०,४४६ एकड़ जमीन की सिचाई होती है।

कृषि विकास में बाधाएँ

‘अधिक अन्न उपजाओ’ सम्बन्धी अभियानों के बावजूद उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने की दिशा में प्रगति नगण्य है। कृषि विस्तार कर्मचारियों ने, ऐसा लगता है कि अर्थ-व्यवस्था पर कोई विशेष छाप नहीं छोड़ी है। इसका कुछ कारण तो यह है कि कर्मचारियों को व्यावहारिक जानकारी तथा अनुभव नहीं था और कुछ कारण यह है कि विभिन्न विभागों में पारस्परिक संयोजन का अभाव था। एक बात यह भी है कि चूँकि क्षेत्र में खेती का काम खेतिहर मजदूरों के जरिये होता है अतः विकास सम्बन्धी कदम इसलिए प्रभावहीन हो जाते हैं कि प्रस्तावित उपायों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए खेतिहर मजदूरों के लिए कोई उत्प्रेरणा

नहीं होती। एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह प्रकार में आया है कि विकास खण्ड में प्रान्यधिकों के लिए वितरित उपकरण इस कदर निम्न कोटि के बताये गये कि प्रात्यक्षिक के दौरान ही या तो वे टूट गये या फिर मुड़ गये तथा अधिकांश को मरम्मत न होने लायक होने की वजह से त्याग दिया गया। सुतार घरों सम्बन्धी सुविधाओं की भी कमी है और ग्रामीण लुहारों तथा बड़ियों को इस काम के लिए प्रशिक्षित करने की व्यवस्था कर उनकी सेवाएँ प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

पशु-पालन के सम्बन्ध में भी स्थिति प्रायः ऐसी ही असन्तोषप्रद है। पशुयोजना क्षेत्र में १,९१,२८८ पशु हैं। इनमें से ७१ प्रति शत गोजातीय हैं। इनसे दूध की प्राप्ति कम होती है और इनकी खींचने की क्षमता भी न्यून है। खीचाई के काम आनेवाले पशु की कार्य-क्षमता करीब ५-६ एकड़ है, जिसका मतलब है खेती सम्बन्धी काम महंगे पड़ते हैं। पशुओं में मृत्योनुपात नौ प्रति शत है। इस प्रकार छोटी-बड़ी खालों और हड्डियों पर आधारित उद्योगों के लिए सम्भाव्यता है। खालों और हड्डियों की औसत सम्प्राप्ति क्रमशः २१,००० नग तथा २५,००० मन है। अधिकांश खालों का निर्यात होता है तथा हड्डियाँ अच्छी-खासी मात्रा में अनुपयोजित पड़ी रहती हैं।

उक्त विकास खण्डों में से एक की ८५,९३५ एकड़ जमीन में से ४१,४०० एकड़ पर पहाड़ व जंगल हैं। एक अन्य विकास खण्ड की ४,६०० एकड़ जमीन पर जंगल हैं। निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण इमारती लकड़ी, नरम तथा सख्त काठ का अधिकांशतः निर्यात होता है। इसी प्रकार ऐसे ही कारणों से बास, तेन्दू के पत्ते, महुआ के उत्पादन, गोद तथा अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियों और फलों जैसे वन्य उत्पादों का भी निर्यात होता है। केवल पाँच प्रति शत महुआ बीजों की ही परम्परागत घानियों में पेरार्ड होती है। लाख उद्योग और टमर कोया-पालन उद्योग तथा चर्म-शोधन सामग्री के उपयोग की सम्भाव्यता के सम्बन्ध

में उपयुक्त खोज-बीन नहीं की गयी है।

बिजली की खपत

प्रौद्योगिक (टेक्नोलॉजीकल) प्रगति को जो लोग बिजली-व्यवस्था का पर्याय मानते हैं, शक्ति-विषय अध्याय से उनकी आँखें खुल जानी चाहिये। दामोदर घाटी निगम के लिए शक्ति पूर्ति की स्थिति सन्तोषजनक बतायी गयी है। चूँकि बिजली का उपयोग करनेवाले पर्याप्त सख्या में आगे नहीं आये, इसलिए विस्तार नहीं किया जा सका। इससे यह निदर्शन मिल जाना चाहिये कि यद्यपि औद्योगिक उपयोग के लिए बिजली की दर घरेलू उपयोग के लिए ३७ नये पैसे प्रति इकाई की तुलना में १५ नये पैसे प्रति इकाई है, तथापि औद्योगिक कामों में उपयोग करनेवालों की सख्या एक सौ से अधिक नहीं हुई।

सहकारी समितियाँ

यद्यपि क्षेत्र में २२५ बहुदेशीय सहकारी समितियाँ हैं तथापि, बताया गया है कि उनमें ४० प्रति शत सख्या ऐसी समितियों की हैं जो या तो बन्द पड गयी हैं अथवा फिर निष्क्रिय हैं। औद्योगिक समितियों की सख्या ८० है। यह बड़े खेद की बात है कि इनमें से अनेक समितियाँ अपने सगठन के समय से ही निष्क्रिय हैं। इससे भी बुरी बात तो यह है कि अनेकों को सगठनात्मक खामियों और ऋण अथवा उपदान की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण ऐसा करना पडा है। लक्ष्याक निर्धारित करने का एक घातक प्रभाव इस पर्यवेक्षण में सामने आता है कि प्रायः समितियों का गठन कारीगरों को सहकारी आधार पर सगठित करने के लिए किसी उद्योग अथवा दस्तकारी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न करके लक्ष्याक पूर्ण करने के लिए किया गया। कुछ भी हो, एक बार जब लक्ष्याको के अनुसार सगठन खडा हो जाय, तो उसके बाद यह सुनिश्चित करना सम्बद्ध अविकारियों का कर्तव्य होना चाहिये कि सहकारी कानून के अनुसार समितियों के हिसाब-किताब का निरीक्षण-परीक्षण होता है। यहाँ तक कि इस आवश्यकता की भी अवहेलना की गयी है, जिसका परिणाम यह

निकला है कि काफी लम्बे अरसे तक लेखा परीक्षण नहीं हुआ।

मौजूदा उद्योगों का सर्वेक्षण इस पर्यवेक्षण के माथ प्रारम्भ होता है कि अधिकांश लोग अपने परम्परागत उद्योगों में लगे हैं। आगे कहा गया है कि "लोगों की अभिरुचि, स्वभाव तथा फैशन में हुए परिवर्तन का बिना मूल्यांकन किये" वे उन्हीं से चिपके रहते हैं। उनके लिए यह अस्तित्व का सघर्ष है। उन्हें रोजगारी के बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं और अगर आज की तरह आर्थिक रूप से काम में लगे रहने की अपेक्षा वे अपने वर्तमान धनो को छोड देते हैं, तो बेकारों की सख्या ही बढ़ायेगे। कुछ पारम्परिक उद्योगों के ममक्ष जो प्रग्न उपस्थित हैं वह जन-स्वभाव के किमी परिवर्तन का नहीं, बल्कि अनेक प्रशोधन उद्योगों के क्षेत्र में उल्टे-सीधे और अनियमित रूप से यात्रीकरण के घुस बैठने का है।

दोष पूर्ण आर्थिक आयोजन

इस सम्बन्ध में उदाहरण के तौर पर यह बताया जा सकता है कि क्षेत्र में ६२ चावल कूटनेवाले हलर हैं। इनमें से सम्भवतः अधिकांश नये हैं। इनकी स्थापित वार्षिक क्षमता ५ लाख ८० हजार मन चावल है। तथापि, वास्तविक उत्पादन केवल १ लाख ८७ हजार मन है। इस प्रकार ६९ प्रति शत क्षमता निष्क्रिय है। इनमें से ५५ इकाइयाँ बिजली का इस्तेमाल करती हैं। दामोदर घाटी निगम सगठन की दृष्टि में यह एक लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही यह एक अच्छा आर्थिक आयोजन नहीं है, क्योंकि क्षमता का आंशिक उपयोग ही हुआ और सात लाख के विनियोजन से एक सौ लोगों को ही मौसमी काम की प्राप्ति हुई। इसी के समक्ष एक दूसरा चित्र यह है कि पारम्परिक हाथ धान कुटाई उद्योग में ३०,००० रुपये के विनियोजन से ९० परिवारों को काम मिला और इस विनियोजन से जिन्हे लाभ पहुँचा उनमें मुख्य रूप से वास्तव में प्रशोधन कार्य में लगे श्रमिक थे। जैसा कि सर्वेक्षण में कहा गया है, चावल कुटाई (हलिंग) उद्योग के विस्तार की और ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

वस्तुतः ग्रामीण औद्योगीकरण के सुझावों में निष्क्रिय क्षमता को हटा देना चाहिये।

औद्योगीकरण की अपनिर्दिष्ट प्रक्रिया का यह कौट छिटपुट यानी एकाध उदाहरण नहीं है, जिसका कुछ लोग समर्थन करते हैं। तेल पेराई उद्योग की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी ही है। क्षेत्र में कोई परिपूर्ण सुसज्जित तेल मिल नहीं है। लेकिन हलरो के साथ कुछ शक्ति-चालित धानियाँ अथवा शेलर हैं। ये बिजली की सहायता से चलते हैं। इकाइयों की संख्या ४६ है और उनकी पेराई क्षमता २२ हजार मन, जबकि पेराई केवल चार हजार मन की हुई। उद्योग से ५० आदमियों को रोजगारी मिली और अतिरिक्त पूँजी विनियोजन हुआ १ लाख २० हजार रुपये का। क्षेत्र की १८० धानियों से २७० व्यक्तियों को काम मिला। यदि यांत्रिक पेराई उद्योग का और अधिक विस्तार किया तो ये बेरोजगार हो जायेंगे। वास्तव में आयोजित विकास के अन्तर्गत शक्ति-चालित यात्रीकरण के प्रवेश को इस क्षेत्र में कोई मान्यता नहीं मिलनी चाहिये थी।

गेहूँ पिसाई के क्षेत्र की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। क्षेत्र में ८५ हजार रुपये के विनियोजन से ६६ आटा चक्कियाँ चल रही थी, जिनकी क्षमता ३ लाख १२ हजार मन पिसाई करने की थी। इस क्षमता के समक्ष उत्पादन हुआ केवल ५४ हजार मन का। इस प्रशोधन उद्योग में हाथ से आटा पीसने के काम से ७,००० महिलाओं को रोजगारी मिलती थी। इसमें भी यात्रीकरण के समावेश से गेहूँ आटा पिसाई उद्योग को 'एक बड़ा भारी धक्का' लगा है। उक्त दो क्षेत्रों की तरह इसमें भी यात्रीकरण के विस्तार की बात नहीं सोची जा सकती। इन तीनों ही क्षेत्रों में उपकरणों और तकनीकों में सुधार करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में, सर्वेक्षण में सुझाया गया है कि राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल को एक सोचा-समझा कार्यक्रम बनाना चाहिये।

कुटीर चर्मोद्योग

प्रारम्भ में छोटी-बड़ी खालों तथा हड्डियों पर आधा-

रित उद्योगों के विकास का जिज्ञास किया गया है। सर्वेक्षण के उत्तरार्ध में इस विषय पर गवच्छेदन से प्रारम्भ कर विस्तार में चर्चा की गयी है। बताया गया है कि यद्यपि ५४५ परिवार गवच्छेदन कार्य में लगे हैं, फिर भी खालों के अलावा गोश्त, चर्बी, सरेग आदि जैसी अन्य चीजें बेकार जाने दी जाती हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि गवच्छेदकों की सहकारी समितियाँ बनायी जायें, उन्हें गोश्त का चूरा बनाने, चर्बी प्रशोधन, सरेग उत्पादन आदि के लिए प्राविधिक रूप से सहायता दी जानी चाहिये। चूँकि अधिकांश हड्डियाँ अनुपयोजित रहती हैं, इसलिए हड्डी-चूर्ण तैयार करने के लिए हड्डी पेरक इकाइयाँ स्थापित करते हुए उनके मनुष्योपयोग पर आधारित उद्योग लाभदायक हो सकते हैं।

चर्मशोधकों के लिए भी इसी प्रकार का सुझाव दिया गया है। फिलहाल ७० केन्द्रों में यह काम होता है। कुल २१,००० खालों के पाँच प्रति शत का ही प्रशोधन होता है। शेष का निर्यात किया जाता है। मौजूदा इकाइयाँ फिलहाल से दम गुनी खालों का शोधन कर सकती हैं, और चर्मशोधन के लिए कच्ची सामग्री भी स्थानीय रूप से उपलब्ध है। जरूरत है कुछ पूँजी की, प्राविधिक मार्गदर्शन की और कच्ची सामग्री तथा बिक्री व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक सेवा सुविधाएँ प्रदान करनेवाले एक संगठन के खड़ा करने की। जूते तथा अन्य चर्मोद्योगी सामान तैयार करने के लिए शोधित चर्म के लिए स्पष्ट स्थानीय बाजार उपलब्ध है। फिलहाल इस प्रकार के सामान की माँग बाहर से मगवा कर पूरी की जाती है अतएव, सर्वेक्षण में इस बात का निर्देशन है कि चर्मोद्योग का विकास करना क्षेत्र के कार्यक्रम का एक अंग होना चाहिये।

खादी उद्योग

जिन अन्य पारम्परिक ग्रामोद्योगों के विकास की गुंजाइश है वे हैं ताड़-गुड़ और बास कार्य। बास उक्त क्षेत्र में काफी तादाद में उपलब्ध है। इस उद्योग में लगे

५०० व्यक्ति कोई एक लाख रुपये के करीब का सामान तैयार कर रहे हैं। यदि सुनियोजित प्रशिक्षण दिया जाय, उन्नत साधन-सरजाम और तकनीको का समावेश किया जाय तथा चन्द सामूहिक सेवाओं का संगठन किया जाय तो ये और भी अच्छी फल-प्राप्ति कर सकते हैं। परियोजना क्षेत्र में ६३९ व्यक्तियों को छेदक बताया गया है। ताड़ के पेड़ ढाई लाख हैं। केवल कुछ ही छेदक छेदन-कार्य में लगे हैं। राज्य में ताड़-गुड़ कार्यकर्ता सहकारी समितियों का एक सघ है। सभी पेड़ों का छेदन करने और इस सम्पत्ति-स्रोत को बेकार न जाने देने के लिए सघ से एक नियमित आयोजित कार्यक्रम बनाने का आवाहन किया जा सकता है।

वस्त्रोद्योग का जिन्न किये बिना ग्रामोद्योगों का कोई भी सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हो सकता। हाथ करघों पर सूती वस्त्र और कम्बले बुनने की तथा रेशम लपेटाई और बुनाई की भी क्षेत्र में काफी गुजाइश है। तथापि, इन घघों में लगे व्यक्तियों की संख्या कोई अधिक नहीं है। क्षेत्र में केवल २३५ सूती हाथ करघा बुनकर, ५५ कम्बल बुनकर और ४७ रेशम बुनकर हैं। खादी काम में लगे बुनकरों की संख्या ८४ है। रेशम कटाई में लगे १३८ व्यक्तियों के अलावा कटाई से ६,६०० व्यक्तियों को काम मिलता है। क्षेत्र में छ त्कुए के अम्बर चरखे का समावेश किया गया है। इस सम्बन्ध में लोगों की ओर से अच्छा प्रत्युत्तर मिला प्रतीत होता है। सर्वेक्षण में इस पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि सुसंयोजित ग्रामीण विकास योजना के अगस्वरूप रूई तथा रेशम कोये, दोनों ही आस-पास से अथवा दूर-दूर से मगवाने पड़ते हैं। ग्रामीण विकास की एक सुसंयोजित योजना में कोया-पालन और उपयुक्त किस्म की कपास की खेती करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

आधुनिक उद्योगों के लिए गुजाइश

उक्त सर्वेक्षण विभिन्न पारम्परिक उद्योगों की सम्भा-

व्यताओं का एक स्थूल सर्वेक्षण है। यह नहीं है कि परम्परागत उद्योगों के सिवाय अन्य उद्योगों की अवहेलना कर देनी चाहिये। सर्वेक्षण में इन सबकी सम्भाव्यता बड़ी अच्छी तरह सामने लायी गयी है। इनमें चन्द इजीनियरिंग, धातु कार्य, पशुओं के लिए सश्लिष्ट चारा तैयार करने, आलू आरक्षण तथा विजलीकरण, चीनी मिट्टी के बर्तन, ईट-पथाई और खपरैल बनाने, कलीदार बाल्टी बनाने, आयुर्वेदिक दवाइयों तैयार करने आदि जैसे उद्योग शामिल हैं। इन सभी उद्योगों का एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाने से, मुख्य आयोजन समिति की स्थायी समिति के मार्गदर्शन में स्थानीय कार्यान्वयन समिति का प्रथम सरोकार होना चाहिये।

उपसंहार

औद्योगीकरण की प्रक्रिया में यह तो एक ही सोपान है। भूतकालीन अनुभव से पता चलता है कि प्रत्येक स्थान पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन का भार जिस अभिकरण पर रहता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। नवादा परियोजना क्षेत्र में, यह सौभाग्य की बात है कि कई रचनात्मक संस्थाएँ हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम निर्माण समिति। उसे परियोजना के लिए प्रवर्तक और कार्य-निष्पादक संस्था के रूप में मान्यता दी गयी है। इसी प्रकार की संस्थाएँ लोक सहयोग प्राप्त कर सर्वांगीण ग्रामीण विकास की कोई भी दूरगामी योजना का निष्पादन कर सकती हैं। आशा है अब बिना किसी प्रकार का विलम्ब किये इस तरह का आयोजन किया जायेगा ताकि देश भर में वैसा करने की होड़ लग जाने का वह आदर्श बने, उससे यह बात सामने आ जाय कि 'नीचे से निर्माण' किस प्रकार प्रभावोत्पादक हो सकता है और 'लोक-आयोजन' का ग्रामीण भारत पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है।

बम्बई २ अप्रैल १९६४

वर्धा घानी से तेल सम्प्राप्ति

राम. कृ. श्रीवास्तव और माधव. रा. देशपाण्डे

घानी की कार्यक्षमता में मामूली सुधार करने से तेलकार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि तब भी उसे एक्सपेलरों की स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अमल में जरूरत इस बात की है कि घानी की पेराई क्षमता में पर्याप्त सुधार किया जाय।

भूतपूर्व खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना तथा उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के गठन से लेकर तेल घानी की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए वर्धा स्थित जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसन्धानशाला में अन्वेषण कार्य चलता आ रहा है। घानी की कार्य कुशलता अनुकूलतम घान और समय के अनुसार उत्पादन अवस्थाएँ बदल कर, मौजूदा घानी की डिजाइन में परिवर्तन करके अथवा नये प्रकार की बैल-चालित घानी का आविष्कार करके सुधारी जा सकती है। कमीशन तेलकारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें अपनी सहकारी समितियाँ बनाने का प्रोत्साहन देता है। घानी तेल केन्द्रों की कुल आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि कितने तेल की बिक्री हुई अर्थात् प्रति घानी प्रति घण्टा कितने तेल का उत्पादन हुआ। चूँकि साधारण घानी की उत्पादन-क्षमता बहुत कम है, इसलिए ऐसी घानी खोज निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं कि उसकी उत्पादकता अधिक हो तथा वह अच्छा काम दे। फिर भी, यदि इस प्रकार की घानी बना ली गयी तो उसका प्रचार-प्रसार करने में समय लगेगा। अतएव वर्धा घानी को एक स्तरीय साधन मानते हुए अधिकतम लाभदायक रूप में तेल सम्प्राप्ति के लिए घान की अनुकूलतम सीमा और समय निर्धारित करने की दृष्टि से उसके तेल निस्सारण का अध्ययन करने का निर्णय किया गया।

प्रयोग

आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद तेल सम्प्राप्ति के लिए

साधारणतया १८ पौण्ड तिलहनो (तिल अथवा मूंगफली) को वर्धा घानी में सवा से डेढ़ घण्टे तक पेरा जाता है। इसलिए पहले उक्त समय में १४ पौण्ड तिलहन पेरा कर और फिर दुबारा १८ पौण्ड तिलहन ले कर तथा समय बढ़ा कर दो घण्टे करके प्रयोग किये गये।

वर्धा घानी में तिलहन पेराई करने के लिए स्तरीय तरीका इस प्रकार है घानी में १८ पौण्ड साफ किये हुए तिल एक घान में डाले जाते हैं। प्रथम बीस मिनट में आवश्यक गरम जल की मात्रा तीन बार में पानी डाल कर दी जाती है। पानी देने का समयान्तर कार्य-कर्त्ता के अनुभव पर निर्भर करता है। साधारणतया आधा घण्टे में तेल दीखने लगता है और घान के पूरा होने में सवा से डेढ़ घण्टे का समय लगता है। इन प्रयोगों के लिए तिलहन स्थानीय बाजार से खरीदे गये थे। तिल मिश्रित जात के थे यानी लाल और सफेद तिल मिले हुए थे। पेराई की योजना इस प्रकार बनायी गयी कि चर कारको की सख्या कम की जा सके।

१. प्रति घान में १४ और १८ पौण्ड तिल पेरेने पर प्राप्त तेल-प्रातिशत्य की तुलना

इन प्रयोगों में १८ पौण्ड के साधारण घान से प्राप्त तेल के प्रातिशत्य का १४ पौण्ड के घान से उपलब्ध तेल के प्रातिशत्य से तुलना की गयी। पेराई का कुल समय डेढ़ घण्टा था। चर कारको को न्यूनतम रखने के लिए एकान्तर दिनों में घानों का क्रम बदला गया, जैसे, प्रथम दिन १८ पौण्ड का घान पहले पेरा गया तो दूसरे दिन

१४ पौण्ड के घान की पेराई पहले की गयी। प्रयोग २८ मई से १३ जून तक किये गये। इस अवधि में दिन का तापमान काफी ऊँचा रहा, इसलिए ३२ औंस पानी देने की आवश्यकता पड़ी। पानी देने और पेराई करने का तरीका 'घानी में तिलहन पेराई के मानक तरीके' के अनुसार रखा गया। प्रयोगात्मक आकड़े तालिका के सेट १ में दिये गये हैं।

२ वर्षा घानी में प्रति घान १८ पौण्ड तिल के घान की डेढ और दो घण्टे पेराई करने पर प्राप्त तेल के प्रातिशत्य की तुलना

इन प्रयोगों में १८ पौण्ड तिल वर्षा घानी में तिलहन पेराई के स्तरीय तरीके के अनुसार डेढ घण्टे तक पेरे गये। अधिकतम तेल प्राप्ति के लिए तिलहनो में पानी देने का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आवश्यक पानी की मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती प्रतीत होती है। मौजूदा प्रयोगों के दौरान जून-जुलाई के मौसम में २४ औंस पानी की आवश्यकता पड़ी। सितम्बर-अक्तूबर

डेढ घण्टे पेराई करने पर प्राप्त तेल का वजन करके लिखा गया। उसके बाद आध घण्टे तक पेराई और जारी रखी गयी—इस प्रकार पेराई दो घण्टे हुई। इसके बाद कुल तेल का वजन कर लिया गया। प्रयोग सम्बन्धी आकड़े तालिका के सेट २ और ३ में दिये गये हैं।

३. अलसी

वर्षा घानी में अलसी की पेराई सम्बन्धी प्रयोग भी किये गये। साधारण तरीके के अनुसार प्रति घान में १२ पौण्ड अलसी ली जाती है। दो या तीन बार में करके २० औंस पानी देना चाहिये। दो-तीन मर्तवा पानी देने में समय का फर्क कार्यकर्त्ता के अनुभव पर निर्भर करता है। पेराई दो घण्टे करनी चाहिये। प्रयोग के लिए पहले दो घण्टे पेराई करने पर प्राप्त तेल का वजन कर लिया गया, उसके बाद पेराई जारी रखी गयी और ढाई घण्टे की कुल पेराई के बाद उपलब्ध तेल का पुन वजन लिया गया। प्रयोग सम्बन्धी आकड़े तालिका के सेट ४ में दिये गये हैं।

वर्षा घानी में तिल और अलसी की पेराई करने सम्बन्धी प्रयोगात्मक आंकड़े

तिलहन	सेट नम्बर	प्रयोग मख्या	तिलहन प्रति घान (पौण्ड में)	समय (घण्टे में)	तेल प्राप्ति प्रातिशत्य	मानक विचलन प्रातिशत्य	प्रति सेट 'टी'*
तिल	१	२०	१४	१ $\frac{३}{४}$	४७ २	० ५४	१ २५
		२१	१८	१ $\frac{३}{४}$	४६ ९	० ६९	
"	२	१२	१८	१ $\frac{३}{४}$	४४ २९	० ६२	२२ ४
		१२	१८	२	४६ १३	० २९	
"	३	२२	१८	१ $\frac{३}{४}$	४३ १७	० ७३	३५ २
		२२	१८	२	४५ ४२	० ४४	
अलसी	४	७	१२	२	३७ ९१	१ २७	७ ६
		७	१२	२ $\frac{३}{४}$	४० ५१	१ १६	

* 'टी' सेट के दो औंसों के अन्तर को मानक विचलन से विभाजित करने पर प्राप्त होती है।

में १८ औंस पानी की जरूरत पड़ी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गर्मी के मौसम में किये गये प्रयोगों के वक्त ३२ औंस पानी देना आवश्यक हुआ।

परिणामों का मूल्यांकन

दोनों प्रकार के प्रयोगों के प्रत्येक सेट के मानक विचलन और गणितीय औसतों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

चूँकि या तो उतने ही समय में कम परिमाण का घान पेरा जाता है या एक समान घान भिन्न-भिन्न समय तक पेरे जाते हैं, इसलिए प्रत्येक सेट का दो क्रमों (सीरीज) में विचरण अर्थात् परिवर्तन अपेक्षित है।

प्रथम सेट के क्रमों की तुलना के लिए 'छात्र की 'टी' का मूल्यांकन करने पर हमें पता लगा कि दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है अर्थात् मानक समय में १४ पौण्ड का घान पेरेने से कोई लाभ नहीं है। और फिर, प्रति घान १४ पौण्ड की पेराई से एक हानि यह है कि १८ पौण्ड का घान पेरेने से प्रति दिन जितना तेल उत्पादन और उसके फलस्वरूप लाभ प्राप्त होता है उसकी तुलना में १४ पौण्ड के घान से दैनिक उत्पादन कम होगा तथा परिणाम-स्वरूप लाभ-प्राप्ति भी न्यून होगी।

द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेट के लिए स्वतंत्र रूप से 'टी' का मूल्यांकन करने से प्रत्येक सेट के दोनों क्रमों के मध्य उल्लेखनीय अन्तर का निदर्शन मिला है अर्थात् आध घण्टे ज्यादा पेराई करने पर प्रत्येक बार ज्यादा तेल प्राप्त किया जा सकता है।

तथापि, नीचे जो हिसाब लगाया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि आध घण्टे ज्यादा पेराई करने पर प्राप्त दो-तीन प्रति शत अधिक तेल से पेरेक को कोई वित्तीय लाभ नहीं होता।

१ यदि डेढ़-डेढ़ घण्टे पांच घान पेरे जाये और औसत निस्सारण ४३ १७ प्रति शत (देखिए सेट तीन, तिल) हो, तो प्रति घानी प्रति दिन तेल उत्पादन ३८ ८५ पौण्ड होगा।

२ यदि दो-दो घण्टों के चार घान पेरे जाये और औसत निस्सारण ४५ ४२ प्रति शत (देखिए सेट तीन, तिल) हो, तो प्रति घानी प्रति दिन तेल-प्राप्ति ३२ ७१ पौण्ड होगी।

यदि तेल का भाव एक रुपया प्रति पौण्ड हो और तेलकार को तेल के मूल्य पर ६ २५ प्रति शत लाभांश

(मार्जिन) मिले तो उसका कुल लाभांश क्रमशः २४३ रुपये तथा २ ०४ रुपये होगा।

उक्त हिसाब से यह स्पष्ट हो जायेगा कि यद्यपि तिल की दो घण्टे पेराई करने पर सम्भव है तेल-प्राप्ति का प्रातिशत्य अधिक हो, लेकिन उसकी डेढ़ घण्टे पेराई करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद है। अलसी के मामले में भी हिसाब लगाने पर पता चलेगा कि दो घण्टों की पेराई ढाई घण्टे की पेराई की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है।

पेराई क्षमता में वृद्धि

अतएव यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक एक समान शक्ति (बैल-शक्ति) के लिए घानी की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि न की जाय तब तक उसकी पेराई क्षमता में मामूली सुधार करने से तेलकार को कोई विशेष वित्तीय लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वह अपने आपको एक्सपेलरों की स्पर्धा का मुकाबला करने में समर्थ नहीं पायेगा, जिनकी क्षमता—छोटे से छोटे 'एक्सपेलर' की भी—घानी से कितनी ही ज्यादा है। यहाँ स्पर्धा एक बीच-बीच में रुक कर चलनेवाली और अनवरत रूप से चलनेवाली प्रक्रिया के बीच है। अनवरत रूप से चलनेवाली प्रक्रिया सामान्यतः सदैव ही बीच-बीच में रुक कर चलनेवाली प्रक्रिया से श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। इस दृष्टि से एक ग्रामोद्योग केन्द्र में बैल-चालित एक्सपेलरों के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं। चूँकि एक्सपेलर को चलाने के लिए काफी अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अभी यह देखना बाकी है कि इस प्रकार का एक्सपेलर आर्थिक दृष्टि से गन्ध है या नहीं।

ये प्रयोग करने में श्री कालू खाँ और अनुसंधान-शाला के तेल घानी विभाग के अन्य कर्मचारियों ने जो सक्रिय सहयोग दिया है, उसके लिए लेखक द्वय उनके आभारी हैं।

वर्षा २८ जनवरी १९६४

विकेन्द्रित कताई और ग्रामीण रोजगारी

केशव ग. देवधर और सौमित्र दे. नाडकर्णी

अम्बर चरखे की कार्य-कुशलता, उत्पादकता और गुण-स्तर में वृद्धि तथा भारपाट में कमी करने की दृष्टि से अहमदाबाद स्थित प्रयोग समिति एवम् खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्षा स्थित केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला में किये गये अन्वेषण के फलस्वरूप उसके प्रारम्भिक नमूने में सुधार किया गया है।

हमारे गाँवों तथा गैर-शहरी क्षेत्रों अर्थात् छोटे-छोटे कस्बों में कपास की खेती से लेकर सूत कताई तक की प्रक्रिया का विकेन्द्रित आधार पर सगठन करने, उसके विकास की गुंजाइश तथा पूर्ण व अर्ध बेरोजगारों को लाभदायक रोजगारी प्रदान करने का सवाल पिछले सात-आठ वर्षों से खादी और ग्रामोद्योग कमीशन व रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के सामने रहा है। यद्यपि पिछले वर्षों में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है, फिर भी कुछ लोगों ने योजना की सफलता एवम् भावी विकास के सम्बन्ध में बे-सिर-पैर की शिकाएँ उठायी हैं।

अन्वेषण

खादी कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, अम्बर चरखे के आविष्कार और १९५५-५६ में उसे क्षेत्र में प्रचलित करने के बाद, हाथ कताई के विकास में पर्याप्त प्रगति हुई है। क्षेत्र में विभिन्न सस्थाओं के तत्वावधान में जो कार्य चल रहा है उसके अलावा, कोई पाँच वर्ष से, मुख्यतः अहमदाबाद स्थित प्रयोग समिति में, और वर्षा स्थित जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला में भी, अन्वेषण कार्य भी चल रहा है। प्रारम्भ में धुनाई मोढिया और बेलनी के साथ अम्बर सेट क्षेत्र में प्रचलित किये गये। क्षेत्र में वितरित और अधिकांश सख्या में सक्रिय अम्बर चरखों पर चलनेवाले काम के साथ ही साथ विकेन्द्रित कताई और पूर्व-प्रक्रियाओं सम्बन्धी अन्वेषण कार्य ने भी सुस्थिर प्रगति की है।

फलस्वरूप विभिन्न एककों में उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने, गुण-स्तर में सुधार करने और प्रति मनुष्य-घंटे सूत-उत्पादन बढ़ाने तथा विभिन्न एककों के संचालन में भारपाट या आवश्यक हस्त-शक्ति की मात्रा कम करने की दृष्टि से कई सुधार किये गये। कई इकाइयों के मामले में पैर-शक्ति या पैडल-संचालन पर भी विचार और प्रयोग किये गये, लेकिन धुनाई मोढिये तथा माला बनानेवाले यंत्र के अतिरिक्त अन्वेषण कार्य में विशेष प्रगति की गुंजाइश दिखायी नहीं पड़ी। परन्तु हाल ही में जिन हस्त-चालित एककों का उनकी डिजाइन तैयार करके निर्माण किया गया है, उनमें पर्याप्त सम्भाव्यता परिलक्षित होती है। ऐसे कुछ एककों का क्षेत्र में प्रचलन किया जा चुका है और कुछ पर क्षेत्रीय परीक्षण चल रहा है। कुछ अन्य इकाइयों की डिजाइने बनायी जा रही हैं तथा उन पर प्रयोग चल रहे हैं।

लाभ

हस्त-चालित साधनों को आसान बनाने के सम्बन्ध में बिल्कुल ठोस परिणाम सामने आये हैं। हाथ को जितनी ताकत लगानी पड़ती थी उसमें काफी कमी की जा चुकी है। पहले जो भारपाट तीन से पाँच पौण्ड तक का था उसमें ५० प्रति शत कमी करके नयी कताई इकाई में वह डेढ़ पौण्ड कर दिया गया है। इसका नतीजा यह निकला है कि सूतकार एक मिनट में हल्वे को ६० से ज्यादा बार घूमा सकता है, जोकि एक औसतन दर्जे के कुशल और

ताकतवर सूतकार के लिए अनुकूलतम ममज्ञा जाना है। विकल्प स्वरूप इस मामले में और हम लाभ के साथ, चालक मन्द गति से अधिक समय तक बिना थकान महसूस किये काम कर सकता है। अन्तिम कताई में पहले, पूर्व-प्रक्रियाओं में काम आनेवाले एककों में सुधार करने से सूत के गुण, मजबूती और ममानता में पर्याप्त सुधार हुआ है।

अम्बर चरखा कार्यक्रम की कुछ लोग जो आलोचना करते हैं उनमें सामान्यतः कार्यवाहक इकाइयों में समाविष्ट नयी डिजाइनों के क्षेत्र में हुई प्रगति अथवा सुधारों और उत्पादकता तथा अन्तिम उत्पादन के गुण में हुए सुधार एवम् फलस्वरूप लाभदायक रोजगारी प्रदान करने के लिए कताई इकाइयों-चरखों-की बड़ी हुई क्षमता के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तीन बेलनों के साथ चार तकुएवाला अम्बर चरखा बड़ा आसान चलने लगा है। अम्बर चरखे के नवीनतम नमूने में छ तकुए हैं। इसमें चार तकुए पक्की कताई और दो तकुए कच्ची कताई के लिए हैं। ये सभी तकुए एक साथ चलते हैं। यह चरखा अहमदाबाद स्थित प्रयोग समिति ने बनाया है। इसे संयुक्त चरखा कहा जाता है। इसका क्षेत्र में प्रचलन किया जा चुका है और उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। छ तकुए के चरखे वर्धा स्थित केन्द्रीय ग्रामीणोद्योग अनुसंधानशाला ने भी बनाये हैं। अनुसंधानशाला द्वारा तैयार की गयी डिजाइन में तकुओं के नीचे तेल की कूपियाँ लगायी गयी हैं। ये चरखे चलाने में हल्के और सुदृढ़ हैं। उत्पादन-क्षमता में भी सुधार हुआ है।

विशेषज्ञों का मत

हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा नियुक्त वस्त्रोद्योग तकनीज्ञों की एक समिति-प्राविधिक समिति, जिसे भूता समिति भी कहा जाता है-ने कताई इकाइयों के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया। समिति ने अहमदाबाद स्थित प्रयोग समिति द्वारा तैयार की गयी विभिन्न डिजाइनों के काम का तुलनात्मक मूल्यांकन किया।

फ्रेम और अन्य पुर्जों की मजबूती, टिकाऊपन में वृद्धि, मरम्मत की कम आवश्यकता, मानकीकरण की प्राप्ति तथा सूत और बट की एकरूपता व गुण में सुधार की दृष्टि से उक्त समिति ने विभिन्न प्रकार के कताई साधनों में चन्द मशोघनों का मुझाव दिया है। चूँकि मूल्यांकन चन्द प्रयोगशाला मजबूती परीक्षणों पर ही आधारित था, इसलिए समिति ने वैज्ञानिक आधार पर क्षेत्रीय परीक्षण करने की आवश्यकता प्रकट की है। लेकिन अब तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वे रोज आठ घंटे के कार्य-दिवस में अथवा छ घंटे कठोर परिश्रम करके एक औसत सूतकार एक रूपये की कमाई करले, इस दृष्टि से आशा-जनक मित्र हुए हैं।

कताई साधनों पर हुए क्षेत्रीय परीक्षणों, विशेषज्ञ समिति के हाल के निष्कर्षों और देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव से विकेंद्रित कताई के क्षेत्र में हुई प्रगति तथा उपयुक्त लाभदायक रोजगारी प्रदान करने की उसकी क्षमता के सम्बन्ध में हम विश्वस्त निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

कताई साधन

डिजाइन, बनावट और कार्य-क्षमता में सुधार करने की दिशा में अन्वेषण जारी है। साथ ही जिन नमूनों का क्षेत्र में प्रचलन किया गया है, उनकी क्षमता के सम्बन्ध में सन्तोषप्रद परिणाम निकले हैं, तथापि छुट्टे पुर्जों के मानकीकरण की दिशा में प्रगति अब भी मन्द है। यह स्पष्ट है कि सूत की मजबूती, एकरूपता और गुण के लिए दबाव, तनाव, गति, केन्द्र और निर्धारित सीध के अनुरूप बिना किसी अन्तर के विभिन्न हिस्से उपयुक्त सन्तुलन एवम् नियमितता के साथ काम दें। इसका मतलब है कि कताई साधनों के सभी हिस्सों की विशिष्टताएँ तथा परिमाण मानकीय हों और उन्हें अनुमत सीमा के भीतर रखा जाय। यत्र मजबूत हो, काम करते वक्त हिले-डुले नहीं और दोषरहित हो।

इन विभिन्न उपकरणों में इन उद्देश्यों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है (१) उत्पादक श्रम करने पर एक

सूतकार एक दिन में कम से कम एक रुपया कमा सके, और (२) किसी दूसरे के लाभ के लिए किसी के श्रम का शोषण अथवा मुनाफाखोरी रोकना। उद्देश्य के रूप में यह भी निरपवाद है कि इन साधनों के निर्माण से ग्रामीण कारीगरों को लाभदायक रोजगारी मिलनी चाहिये तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध काठ जैसी कच्ची सामग्री से इनका निर्माण भी ग्राम्य कारीगरों को करना चाहिये।

लेकिन यदि इस शर्त से साधन की परिशुद्धता, मानकीकरण और कार्यक्षमता में किसी तरह की क्षति पहुँचे तो उस हालत में इसमें ढिलाई की गुंजाइश होनी चाहिये। उदाहरणार्थ, हाल ही में चरखे के लिए धातु के फ्रेम की सिफारिश की गयी है। इसे अथवा अच्छे पके हुए काठ के साथ धातु का उपयुक्त इस्तेमाल करते हुए ऐसे फ्रेम को निश्चय ही तरजीह देनी चाहिये कि यातायात के दौरान उसकी शक्ल न बिगड़े, कहीं टूट-फूट न हो आदि। बार-बार मरम्मत आदि करने की आवश्यकता न पड़ने के सम्बन्ध में इसका जो महत्व है, उसकी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती।

मानकीकरण की समस्या

जहाँ-कहीं छुट्टे पुज या कताई साधन का अन्य कोई हिस्सा—उदाहरण के लिए तकुवा, घिरी आदि—स्थानीय कारीगर, दस्तकार अथवा छोटे-छोटे सुतार घर बनाते हैं वहाँ उनमें बहुत अधिक विभिन्नता रह सकती है—उस अवस्था में तो और भी अधिक जबकि छुट्टे हिस्से अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कारीगर बनाये। जब तक कम से कम हिस्सों को मापने के लिए सुवरी हुई 'सीमा गेज' न प्रदान की जाये तब तक कोई भी मानकीकरण सम्भव नहीं है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही दिशाओं में अथवा अनुमत अधिकतम और न्यूनतम परिमाणों के लिए सीमाएँ निर्धारित करनी ही होगी। जो हिस्से निर्धारित परिसीमाओं के मुताबिक न हो उन्हें खारिज किया जाना चाहिये। जहाँ उपयुक्त

केन्द्रीकृत भण्डार (स्टार) रखे जाते हैं—और इससे बचा नहीं जा सकेगा—वहाँ यह काम उक्त भण्डारों का होगा। इस तरह के कामों के लिए विस्तृत विकेन्द्रित उत्पादन की कल्पना केवल तभी की जा सकती है, जबकि इस काम के लिए औद्योगिक सहकार अथवा सहकारी सुतार घर हो जोकि इनका काम अपने हाथ में ले अथवा फिर कोई प्रमुख संस्था स्वयम् उस काम को चलाये। इसके लिए कुछ स्थानों पर लघु वस्त्रोद्योग प्रयोगशालाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी अथवा फिर फिलहाल पास-पड़ोस में जो प्रयोगशालाएँ हैं उनकी सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

सूतकार

गाँवों में कताई अपनानेवालों में अधिकांश महिलाएँ हैं—यद्यपि कुछ क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या भी काफी है। वे या तो आंशिक धंधे के रूप में या पूर्ण-कालीन काम के तौर पर कताई-कार्य अपनाते हैं। प्रति कार्य-दिवस में वे ७५ नये पैसों से १ ५० रुपया तथा उससे भी ज्यादा कमा लेते हैं। कताई में प्रति दिन वे कितना समय देते हैं अर्थात् कितने वक्त कताई करते हैं, यह उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और मुविधा पर निर्भर है। जो लोग लाभदायक धंधा अपनाना चाहते हैं और जिनका स्वास्थ्य तथा ताकत औसत दर्जे की है वे निश्चय ही इसे पूरे समय के काम के रूप में अपना सकते हैं। छ घण्टे काम करके वे एक रुपया अथवा उससे भी अधिक कमाई कर सकते हैं। प्रशासन के स्तर पर कभी-कभी कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं, जैसे, सूतकारों को समय पर रूई का न मिलना अथवा समय पर अपनी कमाई का न मिलना। ये ऐसे कारक हैं जो अनेक मामलों में लोगों द्वारा कताई को एक नियमित अथवा सुव्यवस्थित धंधे के रूप में अपनाने के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। वस्तुतः सुतारी काम, मरम्मत, प्रतिस्थापन अथवा बदलाई आदि जैसी कारीगरों की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ हैं जो वास्तव में उपयुक्त रूप में और वह भी समय पर पूरी करनी होगी।

इस प्रकार, जहाँ चरखे की डिजाइन में आगे का सुधार किया जाता रहेगा, वहाँ यह कहा जा सकता है कि एक औसत दर्जे के स्वस्थ और पुष्ट शरीरवाले कर्मी के लिए यदि उसे एक ठोस कताई साधन एवम् समय पर अच्छी रुई की पूर्ति का आश्वासन मिले तो विकेंद्रित कताई को नियमित रूप से अपनाना तथा एक दिन में कम से कम एक रुपया कमाने में समर्थ बनना सम्भव है। एक बहुत ही उत्साही और ताकतवर सूतकार आठ घण्टे के साधारण काम से अथवा छ या साढ़े-छ घण्टे के कठोर परिश्रम से डेढ़ रुपये तक भी कमा सकता है। फिर भी, यह समझ लेना है कि विभिन्न क्षेत्रों के तापमान और

सापेक्षिक आर्द्रता का उत्पादकता पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ता है। इस बात का क्षेत्र में सही-सही पता लगाना अभी बाकी है। मब से ज्यादा महत्व है अनुशासन, समय और कार्य-क्षमता का। कुटीर उद्योग को अगर लाभदायक रोजगारी के रूप में अपनाना है तो उसका मतलब होना चाहिये कारखाने से कुटीर में काम करने के वातावरण का परिवर्तन, लेकिन उसका अर्थ काम के प्रति सजगता का अभाव और काम के घटो में शैथिल्य नहीं होना चाहिये। लाभदायक रोजगारी अनिवार्यतः अनुशासन पूर्ण काम पर निर्भर है।

बंबई १ अप्रैल १९६४

मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरी प्राचीन पद्धतिवाली सुसंस्कृत शिक्षा ने मुझे १९वीं शताब्दी की जर्मन पद्धति के अनुसार मानव-शास्त्र की पढाई से बचा लिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि १५वीं शताब्दी की इटालवी पद्धति बेहतर थी; क्योंकि मेरे खयाल से मानव-जीवन के प्रति वह ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो अधिक सच्चाईपूर्ण है। प्राचीन मानवीय शास्त्र के विद्यार्थी को बताया जाता है कि यूनानी-रोमन जीवन में एकता है। उसकी दृष्टि में भाषा, साहित्य, कल्पनाशील कलाएँ, धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा उसके परिनिष्ठित संसार का इतिहास अलग-अलग विषय नहीं हैं, वे सब जीवन की एकरूपता के विभिन्न पक्ष हैं; और इन सब को तथा किसी एक को तब तक अच्छी तरह नहीं देख सकते, जब तक समस्त अंगों को 'पूर्ण' के ही सारभूत अवयव-स्वरूप न देखें।

— अर्नाल्ड जे. टायनबी : जेनस ऐट स्लेवण्टी फाइव ।

उत्तर प्रदेश में गुड़ की सहकारी विक्रय-व्यवस्था

भारत भूषण कंसाल

प्रस्तुत लेख में उत्तर प्रदेश में गुड़ की सहकारी विक्रय-व्यवस्था के सगठन पर विचार किया गया है, सहकारी समितियों के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है और कुछ ऐसे सुझाव दिये गये हैं जिनसे उनके कार्य संचालन की नींव मजबूत बनने में सहायता मिलनी चाहिये।

सहकारी विक्रय-व्यवस्था (मार्केटिंग) का बुनियादी सिद्धांत है यह सुनिश्चित करना कि कृषक को अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो तथा एक ओर उपभोक्ता द्वारा अदा की जानेवाली और दूसरी तरफ कृषक को प्राप्त होनेवाली कीमत के बीच का अन्तर कम हो। ससार के अनेक भागों में, यह दलितों को आर्थिक राहत प्रदान करने का साधन नहीं है।

गाँवों में उत्पादन की स्थानीय निकासी के प्रमुख कारण हैं (१) बिक्री के लिए अतिरिक्त माल की कम तादाद का होना, (२) खेत से उत्पादन को कारखानों, मिलों, निर्यातक और उपभोक्ता तक पहुँचाने हेतु परिवहन के लिए आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने में किसानों की असमर्थता, और (३) पूर्ति का माग के साथ समझन करने के लिए अपने पास शक्ति रखने की कमी। किसान शोषण का शिकार हैं, क्योंकि वह अपना उत्पादन दलाल के मार्फत बेचता है। चूँकि वह अपना उत्पादन व्यक्तिगत रूप से बेचता है, इसलिए उसे अपने माल की उचित कीमत नहीं मिल पाती। उसे उपभोक्ता द्वारा अदा की जानेवाली कीमत का उचित हिस्सा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उत्पादन की बिक्री एक सगठित और नियमित बाजार में ही होनी चाहिये, जहाँ माग तथा पूर्ति में समुचित सम्बन्ध हो। द्वितीय, वितरण खर्च कम से कम किया जाना चाहिये तथा वाणिज्य में जो बुराईयें हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये। तृतीय, बाजार में जब माल की भरमार हो, मन्दी आ गयी हो तो, जब तक भाव सुधर न जाये तब तक के लिए अपना माल बाजार में न

भेज कर अपने पास रखने की शक्ति उसे यानी कृषक को प्रदान की जानी चाहिये।

सहकारी विक्रय-व्यवस्था समिति अन्य सहकारी संस्थाओं के समान ही उत्पादकों का एक सगठन है। उत्पादकों के सामूहिक हित को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से उसका प्रबन्ध होता है। सर्वे सही शब्दों में इसे यों कहा जा सकता है कि कृषि उत्पादनों के सम्बन्ध में सहकारी विक्रय-व्यवस्था व्यापारी तौर-तरीकों का एक प्रयोग है। खाद्य और कृषि सगठन^१ (फूड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन) ने सहकारी विक्रय-व्यवस्था के उद्देश्य और लाभ बड़ी अच्छी तरह इन शब्दों में व्यक्त किये हैं। “प्रत्येक विक्रय-व्यवस्था सहकारी समिति का उद्देश्य है अपने सदस्य के उत्पादनों की सर्वोत्तम बाजार और उस राज्य में बिक्री करना जहाँ सर्वोत्तम मूल्य-प्राप्ति हो सके। छोटे-बड़े सभी उत्पादकों को वह समान सेवा प्रदान करती है। सर्वोत्तम माल और सर्वाधिक मागवाले उत्पादन तैयार करने में वह सदस्य की सहायता करती है। वह सही माप-तौल करती है। उत्पादन को वह इस प्रकार श्रेणीबद्ध करती है कि सभी किस्म के उत्पादनों का उत्पादक के हक में सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त किया जा सके। फसल को बिना किसी नुकसान अथवा बर्बादी के माफ तौर पर इस ढंग से सम्हालना उसका उद्देश्य है कि वैसा करने से उत्पादन की कीमत घटे नहीं, बल्कि बढ़े। वह

^१ एग्रीकल्चरल डेवलपमेण्ट पेंपर नम्बर ५३

‘कोऑपरेटिव मार्केटिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स’, खाद्य और कृषि सगठन।

सद्व्यवहार के लिए है। गुटबाजी और कीमतों में हेरा-फेरी के विरुद्ध वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करती है। उचित शर्तों के अनुसार अग्रिम रकम देकर वह मदस्य की वित्तीय सहायता करती है, जबकि वह अपनी फसल के पकने का इन्तजार करता है। अच्छे और बुरे वर्ष का अन्तर मिटाने के लिए वह यथा शक्ति जो कुछ कर सकती है, करती है। जो कुछ अनिश्चित प्राप्त होती है, वह मदस्यो में उनके योगदान के अनुपातानुसार बराबर-बराबर बाँट देती है। वह किसान को विक्रय-व्यवस्था सबी प्रक्रिया की सभी अवस्थाओं की अच्छी समझ प्रदान करती है।”

भारत में सहकारी विक्रय-व्यवस्था

भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रवर्तन आधिकारिक तौर पर १९०४ के सहकारी ऋणदात्री समिति अधिनियम के साथ हुआ। तत्सम्बन्धी दूसरा महत्वपूर्ण कदम था १९१२ में एक अन्य केन्द्रीय कानून का बनना, जिसमें गैर ऋणदात्री और केन्द्रीय समितियों का संगठन सामने आया। आजादी हासिल करने से पूर्व सहकारी समितियों का विकास कार्यक्षेत्र और सीमा दोनों ही दृष्टियों से सीमित था। स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ सहकारी आन्दोलन ने द्रुत और बहुविध विकास के युग में पदार्पण किया। एक ‘सहकारी समाज’ की स्थापना हमारी सामाजिक और आर्थिक नीति का लक्ष्य घोषित किया गया है। तीनों ही पंच वर्षीय योजनाओं में सहकार को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। प्रथम योजना^२ में कहा गया है कि सहकारी संगठन “लोकतंत्र में आयोजित आर्थिक कार्य का एक अपरिहार्य अंग है।” दूसरी पंचसाल योजना में आयोजित विकास योजना के अंग स्वरूप सहकारी विभाग का निर्माण करना राष्ट्रीय नीति के एक प्रधान उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया गया है।^३ इसी प्रकार तृतीय योजना में आर्थिक जीवन की अनेक दिशाओं में—खास कर कृषि और लघु सिंचाई, लघु उद्योग और प्रशोधन, विक्रय-व्यवस्था, वितरण, पूर्ति आदि के क्षेत्र में—सहकार

^२ प्रथम पंच वर्षीय योजना, भारत सरकार, पृष्ठ १९३।

^३ द्वितीय पंच वर्षीय योजना, भारत सरकार, पृष्ठ २२१।

संगठन का प्रधान आधार बताया गया है।^४

भारत में सहकारी विक्रय समितियों का ढाँचा ऋणदात्री सहकारिताओं के अनुसार त्रि-सूत्री है—बुनियादी तौर पर प्राथमिक सहकारिताएँ, जिले अथवा उसके किमी हिस्से के लिए, केन्द्रीय मध्य अथवा परिपद और राज्य स्तर पर शीर्ष सस्थाएँ। अधिकांश राज्यों में राज्य स्तरीय सस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं। केवल १९१२ के बाद से ही गैर ऋणदात्री समितियों का संगठन हुआ है और १९३०-३१ तक उनकी कुल संख्या नगण्य अर्थात् ८४९ ही थी।^५ इसलिए गैर ऋणदात्री सहकारी समितियों का ढाँचा विकास की अवस्था में है, उसे अभी एक सुविकसित संगठन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रथम, व्यावहारिक आवश्यकताओं तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग उत्पादनों की समितियों के संगठनात्मक स्वरूप में विभेद पाया जाता है। अनेक मामलों में द्वि-सूत्री संगठन है—या तो उक्त त्रि-सूत्री संगठन में से बीचवाला संगठन नहीं है या फिर शीर्ष संगठन और सामान्यतः शीर्ष संगठन ही नहीं होता। उत्तर प्रदेश में घी और दूध सम्बन्धी समितियों का मामला कुछ ऐसा ही है तथा हाल ही तक गन्ना सहकारी संघों का भी ऐसा ही था। द्वितीय, शीर्ष संगठन साधारणतया सामग्री के अनुसार नहीं होता। किसी एक ही पद्धति पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी विक्रय-व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में पहले सहकारी विक्रय-व्यवस्था की ओर कोई विशेष झुकाव नहीं था। घी की बिक्री के लिए चन्द समितियों ने सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त किये, लेकिन वे सदैव ही अलग-अलग स्वतंत्र इकाइयाँ रही, और उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत नहीं हुआ। फिर भी, आधुनिक चीनी उद्योग के विकास के साथ गन्ना पूर्ति समितियाँ बनीं। उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है और

^४ तृतीय पंच वर्षीय योजना, भारत सरकार, पृष्ठ २००।

^५ आर एस श्रीवास्तव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इण्डिया एण्ड एब्रोड।

कुल मिला कर देखने पर वे अच्छा काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी विक्रय-व्यवस्था समितियों की तीन विशिष्ट श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी है विक्रय सघों की। हाल ही में इन्होंने प्राथमिक स्तर पर खड सघों का रूप ले लिया है। (ग्रामीण क्षेत्रों में खड सघ सब से छोटी इकाई है और वह विक्रय-व्यवस्था तथा पूर्ति सम्बन्धी काम करता है। खड सघ का उद्देश्य है ग्रामीण को उस प्रकार की कृषि-विषयक आवश्यकताएँ मुहैया करना जो अन्य किसी भी प्रकार का सहकारी अभिकरण (एजेसी) नहीं कर सकता। खड सघों का विकास १९४७ में नव विकास योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हुआ। पूर्ति सम्बन्धी काम के अलावा खडीय सघ विक्रय-व्यवस्था का काम भी करता है।)

जिला स्तर पर जिला सघ है, जिनके राज्य स्तर पर प्रादेशिक सहकारी सघ हैं। (सभी खड सघों से मिल कर जिला सहकारी सघ बनता है, जो बैंकिंग के अलावा अन्य सभी प्रकार के काम करने के लिए जिले का प्रधान सगठन होता है। प्रादेशिक सहकारी सघों के सामान्य नियंत्रण और देखरेख के अन्तर्गत रहते हुए जिला सहकारी सघ से अपेक्षा की जाती है कि वह जिले में सहकारी गतिविधियों में भार्गदर्शन देगा, पर्यवेक्षण करेगा, नियंत्रण रखेगा और समन्वय लायेगा। प्रत्येक जिले में एक जिला सहकारी सघ है और साधारणतया वह कच्चे माल, उपभोक्ता सामग्री और कार्यकुशल कृषिक उत्पादन के लिए आवश्यक उन्नत साधन-सरजामों का एकमुश्त वितरण करता है। प्रादेशिक सहकारी सघ राज्य स्तर पर विक्रय-व्यवस्था, वितरण और वाणिज्य सम्बन्धी कामों के लिए एक शीर्ष संस्था है। इसका गठन जुलाई १९५३ में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न अवस्थाओं के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ। यद्यपि १९४१-४२ में जीवन की अनेक आवश्यकताओं सम्बन्धी चीजों के दामों पर सरकार का नियंत्रण था, तथापि, नियंत्रण प्रभावहीन बन गया था और कीमते काफी बढ़ गयी थी। चारों ओर असहाय्यता की भावना

फैली हुई थी और मुनाफाखोरी का बोलबाला था। ऐसी परिस्थितियों में कुछ जिलों के जिला न्यायाधीशों ने उपलब्ध गेहूँ और आटे के स्टॉक अपने कब्जे में ले लिये और सहकारी समितियों के सहायक पजीयकों को अपने कार्यक्षेत्रों में इन चीजों के वितरण की जिम्मेदारी दी। प्रत्येक जिले में सहायक पजीकार को जिस नियंत्रित सामग्री के वितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, उस काम में सहायता देने के लिए एक-एक सहायक सुपरिण्डेण्डेंट होता था। चूँकि यह काम करने के लिए कोई उपयुक्त सहकारी सगठन नहीं था, इसलिए सहकारी विकास और विक्रय-व्यवस्था सघ स्थापित होने तक सहायक पजीयक यह काम करता रहा। अब उक्त सघ का नाम बदल कर प्रादेशिक सहकारी सघ कर दिया गया है। यहाँ तक कि इससे पूर्व विक्रय-व्यवस्था सघों—जिन्हें आगे चल कर विकास खड सघों में रूपांतरित कर दिया गया—की कार्यशीलताओं में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रातीय सहकारी सगठन खडा करने के सवाल पर राज्य का सहकारी विभाग सक्रिय रूप से विचार कर रहा था। अतएव सघ के उद्देश्य, जैसा कि उसके उपनियमों में बताया गया है, यथा सम्भव व्यापक है, ताकि उसके कार्यक्षेत्र में विक्रय-व्यवस्था और वितरण दोनों सम्बन्धी कार्य शामिल हो सके।)

दूसरी श्रेणी है गन्ना उत्पादक सघों की। गन्ना उत्पादक यानी कृषक और गन्ना आयुक्त—जोकि गन्ना उत्पादक सहकारी सघों का पजीयक भी है—के अन्तर्गत गन्ना विकास विभाग नामक अलग विभाग द्वारा प्रबन्धित समितियाँ भी उक्त सघों से सम्बद्ध हैं। एक अलग नियंत्रक अधिकारी का होना आवश्यक समझा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना विक्रय-व्यवस्था का काम सहकारी विक्रय-व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पक्ष है।

तीसरी श्रेणी में घी सघ आते हैं। राज्य में सहकारी विक्रय-व्यवस्था समितियाँ इनसे सम्बद्ध हैं।

अब हम गुड उद्योग की मौजूदा सहकारिताओं के

वास्तविक कार्य का परीक्षण कर, उनके दावों पर दृष्टि डालें और सुधार का सुझाव दें ताकि राज्य की अर्थ-व्यवस्था में समितियाँ अपनी उपयुक्त भूमिका निभा सकें। गुड उद्योग में—खास कर राज्य के पश्चिमी हिस्से में—सहकारी समितियाँ हाल ही में आगे आयी हैं। प्रायः प्रत्येक छोटी या बड़ी मण्डी कम से कम एक सहकारिता बनाने की कोशिश कर रही है। ये गुड सहकारी समितियाँ अन्य सहकारियों के समान ही या तो लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश के सहकार पञ्जीयक अथवा फिर हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त उप पञ्जीयकों के पाम पञ्जीकृत हैं। एक सहकारी वित्तीय-व्यवस्था समिति की सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं

१ **सदस्यता** किसी समिति की सदस्यता के अन्तर्गत सदस्यों की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ होती हैं, उदाहरणार्थ (क) सहकारी समितियाँ—‘अ’ श्रेणी, (ख) स्वतंत्र उत्पादक—‘आ’ श्रेणी, (ग) मण्डियों के व्यापारी—‘इ’ श्रेणी, और (घ) राज्य सरकार, जोकि यदि किसी श्रेणी (सामान्यतः ‘अ’ श्रेणी को तर्जनी दे दी जाती है) के हिस्से खरीदे तो उसे ‘विशिष्ट सदस्य’ माना जाता है। ‘अ’ श्रेणी के सदस्य को १०० रुपये के एक हिस्से में अशदान देना पड़ता है, ‘आ’ श्रेणीवाले को २० रुपये के एक हिस्से में और ‘इ’ श्रेणीवाले को एक रुपये के एक हिस्से में।

२ **पूँजी** समिति की पूँजी में यह पूँजी आती है (१) हिस्सा पूँजी, (२) ऋण, (३) दान, (४) आरक्षित कोष, (५) विशेष योगदान, और (६) राज्य उपदान। **हिस्सा पूँजी** प्रत्येक सदस्य को पूरी कीमत चुका कर हिस्सा खरीदना पड़ता है। यही वह मुख्याधार है, जिस पर समिति का वित्तीय भवन खड़ा होता है। हिस्सा पूँजी जितनी ही अधिक होगी काम का क्षेत्र उतना ही व्यापक होगा और अन्य वित्तीय स्रोतों पर निर्भरता उतनी ही कम। **ऋण** वित्त की कमी ऋण प्राप्त करके पूरी की जाती है। ये ऋण या तो केन्द्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त किये जाते हैं या स्टेट बैंक में अथवा फिर सरकार या अन्य किसी बैंक से। उत्तर

प्रदेश में सहकारी समितियाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक से १,००,००० रुपये तक ऋण ले सकती हैं। बड़ी मण्डियों में ऋण की रकम बढ़ा कर १,००,००० रुपये से ३,००,००० रुपये कर दी गयी है। अखिल भारत ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति ने जिस मुमयोजित सहकारी योजना की सिफारिश की थी उसके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में नीची व्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं। व्याज दर भिन्न-भिन्न है। केन्द्रीय सहकारी बैंक ७ ५ प्रति शत व्याज लेता है और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ५ प्रति शत। दान अनेक धर्मार्थ और जनकल्याणकारी समितियों के लिए दान और उपहार प्रत्याशित वित्तीय स्रोत समझ जाते थे। राजा-महाराजाओं, जमींदारों आदि के पतन के साथ ये स्रोत भी सूख गये। **आरक्षित कोष** सहकारिताओं के ‘आदर्श उपनियमों’ में इस बात की व्यवस्था है कि विशुद्ध लाभ का २५ प्रति शत हिस्सा अधिलाभ घोषित करने से पूर्व ‘आरक्षित कोष’ में स्थानान्तरित किया जाना चाहिये, ताकि उसका बुरे वर्ष में इस्तेमाल किया जा सके। **विशेष योगदान** मण्डी में प्रायः कुछ अन्युदार उत्पादक इस आशा से आगे आकर सहकारी समिति की विशेष योगदान दे कर सहायता करते हैं कि एक दिन वे इस विकासशील पेड़ के फल चख सकेंगे। इस प्रकार के योगदान का बहुत महत्व है, क्योंकि वह उस वक्त प्राप्त होता है, जबकि उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश सहकारिताएँ इस अत्युदारता का फायदा नहीं उठा सकी, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ‘सहकार’ लोगों के अन्दर से विकसित नहीं हुआ, बल्कि ऊपर से थोपा जा रहा है। **राज्य उपदान** सहकारिताओं को अपना कार्यारम्भ करने में समर्थ बनाने के लिए प्रारम्भिक वर्षों में राज्य अर्थात् सरकार प्रबन्ध खर्च के लिए उपदान देती है।

संगठन और नियंत्रण

समितियों के संगठन और नियंत्रण के लिए दान कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है (१) मंत्री-

सह-प्रबन्धक, (२) लेखापाल-सह-गोदाम कार्यभारी, (३) मुनीम, (४) चपरासी, और (५) चौकीदार। इनमें से प्रथम दो की नियुक्ति सरकार करती है और उनका वेतन भी वही देती है। ये प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। उनका वेतन क्रमशः १२० रुपये और ७५ रुपये मासिक होता है। मुनीम अथवा मुनिमो (उनकी सख्या समिति के व्यवसाय पर निर्भर करती है) की नियुक्ति स्वयम् समिति करती है। ये मुनीम लेखापाल को उसके काम में मदद देते हैं तथा समिति के लिए 'विक्रेता' का काम भी करते हैं। कभी-कभी व्यस्त मौसम-काल में कुछ समय के लिए सहायक मुनीम रखे जाते हैं। सामान्यतः एक मुनीम का वेतन उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार ७०-८० रुपये प्रति माह होता है। चपरासी-सह-चौकीदार की नियुक्ति भी समिति ही करती है। कभी-कभी एक ही व्यक्ति चपरासी और चौकीदार, दोनों का काम करता है। इन चपरासियों तथा चौकीदारों का वेतन साधारणतया ४५ रुपये मासिक होता है।

कार्य-प्रणाली

समितियों की कार्य-प्रणाली बड़ी सरल है। मण्डी में समिति कच्चे आड़तियों के रूप में काम करती है अर्थात् अपने सदस्यों से-कभी-कभी गैर-सदस्यों से भी-उत्पादन खरीदती है और पक्के आड़तियों के मार्फत उपभोक्ताओं को उसकी बिक्री करती है। उनके सौदे की एक विशेषता यह है कि उन्होंने बिक्री-खर्च कम कर दिया है।

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि समितियाँ पक्के आड़तियों का भी काम क्यों नहीं करती? इसके कई कारण हो सकते हैं। सर्व प्रथम, सहकारी समितियाँ अभी तक बाजार में जन्म नहीं पायी हैं और उन्हें कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। द्वितीय, अभी तक वे अन्य राज्यों में उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पायी हैं। तृतीय, जोकि बहुत महत्वपूर्ण है, उच्च स्तर के सधों ने अभी तक पक्के आड़तियों में नमस्कार कर लेने में समितियों की सहायता करने में दिलचस्पी नहीं ली है। परिणाम

यह निकला है कि अधिकांश समितियों को अपने सदस्यों के माल की बिक्री के लिए पक्के आड़तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ मामलों में, जब पक्के आड़तिये सहकारी का बहिष्कार करते हैं तो, सध आगे आ कर सहकारिताओं की मदद करते हैं।

इस प्रकार समितियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि सहकारी विक्रय-व्यवस्था में सहकारिताओं को अपनी उपयुक्त भूमिका निभानी है तो यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल किया जाय। समितियों के मामले मुख्य बाधाएँ आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की हैं। बाह्य समस्याएँ इस प्रकार हैं (१) बाजार में काम करनेवाले अन्य माध्यमों की ओर में विरोध। इन माध्यमों ने एक तरह से अपने पैर बड़े पक्के जमा रखे हैं। समितियों को आड़तियों से कड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है। ये आड़तिये अपने हित-साधन के लिए हर प्रकार के तरीके अस्तित्वार करते हैं, (२) समितियाँ प्रायः अपनी ढूँढ़ने मण्डियों से दूर खोलती हैं, क्योंकि मण्डी के भीतर उन्हें उपयुक्त स्थान और भोजन नहीं मिल पाता। भाण्डारीकरण सम्बन्धी मुविधाओं के मामले में वे बड़े घाटे में रहती हैं। इन कारणों से अनेक उत्पादक खरीदार उन तक नहीं पहुँच पाते, और (३) उत्पादक को अपनी ओर खींचने अथवा खरीदार को सहकारी समिति की ओर जाने से रोकने के लिए आड़तिये हर तरह के उपाय काम में लाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सहकारी समितियाँ इस प्रकार के तरीके अस्तित्वार नहीं कर सकती। बाजार भाव से नीची अथवा ऊँची दर पर बीजक बनाना कुछ मण्डियों में प्रचलित एक आम बात है।

आन्तरिक बाधाएँ, जो ओर भी भीषण हैं, इस प्रकार हैं (१) पक्षपात, नौकरशाही, लालफीताशाही अथवा सोदे में देर आदि आम रुकावटें हैं। उदाहरण के लिए, उत्पादक को ऋण देने में विलम्ब करने का फल प्रायः यह निकलता है कि उसे बाध्य हो कर मण्डी में आड़तियों में आवश्यक अर्थ प्राप्त करना पड़ता है। ये वित्तीय

सम्बन्ध कृषक को आगामी मौसम में कच्चे आड़तियों के साथ व्यवहार करने के लिए बाध देते हैं, (२) अपर्याप्त वित्त दूसरी बाधा है। जब व्यस्त मौसम के दौरान मण्डी माल से भर जाती है, तो समितियों के पास प्रायः वित्त की कमी पड़ जाती है और वे अपने सदस्यों की सहायता करने अथवा उत्पादकों में अपने को लोकप्रिय बनाने का अवसर खो बैठती हैं। इसमें उनके बजट तथा कुल काम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और (३) सदस्यों की निष्ठा भी शकास्पद है। ऐसा पाया गया है कि कार्यकारिणी के सदस्य तक अपना माल इनके जरिये नहीं बेचते। इसका कारण एक तो यह है कि उन्हें समिति की पूरी स्थिति—उसकी कमजोरी सहित—की परिपूर्ण जानकारी होती है तथा द्वितीय यह कि प्रायः समिति को बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिसे समिति के जरिये बिक्री करने पर अधिकारियों को हानि उठाने की सम्भावना रहती है।

सुधार के लिए सुझाव

कुछ अन्य बाधाएँ भी हैं। इन सब पर सौवधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सहकारिताओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं

(१) बाह्य उपभोक्ताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये, ताकि पक्के आड़तियों द्वारा समितियों का बहिष्कार करने पर भी कोई सकट न रहे। (२) उच्च स्तरीय सहकारी सघों को न केवल वित्त से ही बल्कि समितियों को अपने माल की बिक्री करने में अपने अनुभव से भी आगे आकर सहायता देनी चाहिये। य सघ समितियों अथवा उनके सदस्यों को ऋण स्वीकार करने सम्बन्धी कार्य-प्रणाली सरल कर सकते हैं और विलम्ब होने से बचा सकते हैं। (३) यदि वित्त हो तो समितियाँ अपनी दुकानों के साथ अर्थात् उनके पास ही गोदाम भी रख सकती हैं। ये गोदाम हवादार हो तथा आर्द्रता से उनकी रक्षा होनी चाहिये। (४) समितियों को परिपूर्ण खरीद और बिक्री करने के अधिकार देने का प्रायः सुझाव दिया

जाता है, ताकि वे समय पर बाजार का फायदा उठा सकें। अपनी खरीद अथवा बिक्री की बात भारी जोखिमवाली है और अनुभवहीन कर्मचारियों, निष्ठा न रखनेवाले सदस्यों, अपर्याप्त वित्त तथा अन्य खामियों के कारण गुंजाइश यह रहती है कि 'कमाई' के बदले 'खोई' अधिक होगी एवम् इस प्रकार समिति का दिवाळा निकल सकता है, जिससे सभी को हानि होगी। यह सुझाव सभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि समितियों के सदस्य निष्ठावान, कर्मचारी अनुभवी और प्रशिक्षित हो तथा सघों का उन पर हाथ हो एवम् सभी तरफ से उन्हें मदद मिले। (५) गुड़ की खाम-खास मण्डियों में नियमित बाजार पद्धतियाँ लागू करने के लिए राज्य को विशेष उपाय काम में लाने चाहिये। दुर्भाग्य से राज्य में अभी तक कोई नियमित बाजार नहीं है। अब वह समय है कि उत्तर प्रदेश सरकार नियमित बाजार पद्धतियाँ लागू करने के लिए कदम उठाये, जिनसे अनियमित बाजार पद्धतियाँ समाप्त करने में सहायता मिलेगी और परोक्ष रूप से सहकारी समितियों को अपने काम में मदद मिलेगी। (६) जहाँ तक स्वयम् समितियों का सवाल है उनके लिए यह सलाह है कि वे 'मुहर दहाये, कोयले पर छाप' वाली नीति के प्रति सजग रहे। अपने प्रारम्भिक काल में खर्च कम से कम करने के लिए समितियाँ कम वेतन पर अनुभवहीन कर्मचारी रख लेती हैं। अच्छा वेतन पानेवाले कर्मचारी एक प्रकार की सम्पत्ति हैं। अनुभवी कर्मचारी रखने चाहिये, क्योंकि उन्हें वाणिज्य का पूरा ज्ञान होता है, आड़तियों की चालाकियों से वे परिचित होते हैं और मण्डी में आनेवाले अधिकांश उत्पादकों से उनकी जानकारी होती है।

अन्त में यह सुझाया जाता है कि उक्त प्रस्तावों का एक 'विशेषज्ञ समिति' वर्तमान अवस्था के अन्तर्गत गहराई से परीक्षण और विश्लेषण करे। ऐसी समिति में राज्य अर्थात् सरकार, वाणिज्य सघों, सहकारी सघों आदि के प्रतिनिधि होने चाहिये।

गाज़ियाबाद • ७ अप्रैल १९६४

मैसूर में ग्राम्य जन-शक्ति परियोजनाएँ

स. म. वीरराघवाचार

मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में पवागदा और गुलबर्गा जिले के यादगिरी नामक स्थानों में १९६०-६१ में दो मार्गदर्शी परियोजनाएँ चलाई गयीं। उक्त दोनों ही क्षेत्र कमीवाले हैं। प्रस्तुत लेख में तीसरी पाँचसाला योजना की अवधि में शुरू किये गये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताओं पर उक्त दो परियोजना क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में चर्चा की गयी है।

बेरोजगारी क्या है ? असल में वह एक ऐसे व्यक्ति की अनिच्छित निष्क्रियता है, जो काम करने के लिए इच्छुक है और वैसा करने में समर्थ है। प्रत्येक देश में यह पायी जाती है—भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार में—और प्रत्येक देश इसका समाधान प्राप्त कर पूर्ण रोजगारी का स्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है। बेरोजगारी के लिए अनेक पहलू उत्तरदायी हैं। मजदूरी की दर की सख्ती, श्रम बाजार की अपूर्णताएँ, एक पूँजीवादी समाज में अपरबचत और अपरविनियोजन की भयंकर प्रवृत्ति, प्रभावक माँग की कमी, पूँजी की कमी और अत्यधिक आबादी इसके कारण बताये गये हैं।

बेरोजगारी के प्रकार

बेरोजगारी की मुख्यतः चार श्रेणियाँ हैं—मौसमी, प्रौद्योगिक (टेक्नोलॉजीकल), सामयिक और अल्प बेरोजगारी अथवा गुप्त बेरोजगारी। मौसमी परिवर्तन, प्रौद्योगिक सुधार और व्यावसायिक घटना चक्र का प्रत्यावर्तन बेरोजगारी के कारण हैं। अल्प बेरोजगारी अधिकांश अल्प-विकसित देशों की एक विशिष्टता है। जी डी एन वारविक के शब्दों में अल्प बेरोजगारी वह “श्रम है जिसका फलहाल हानिकर उपयोग होता है।” अल्प बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रम-शक्ति “न तो पूरी तौर पर काम में ही लगी होती है और न पूर्णरूपेण बेकार ही।” अल्प बेरोजगारी के शिकार वे व्यक्ति हैं जो अपना काम करते हैं और अर्थ-व्यवस्था के जिस क्षेत्र में वे काम करते हैं उसमें उनकी सख्या इतनी अधिक है कि यदि कुछ लोग उस

क्षेत्र से हट भी जायें तो भी कुल उत्पादन में कमी नहीं आयेगी। विकसित देशों में उपलब्ध स्थिति के विपरीत अल्प विकसित देशों में श्रम का सीमान्त उत्पादन बहुत ही नगण्य अथवा यहाँ तक कि नकारात्मक है। इस प्रकार कृषि में लगी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को कुल उत्पादन में बिना कोई कमी किये अन्यान्य धंधों में लगाया जा सकता है। जहाँ यह सच है कि भारत में मौसमी, घटना चक्रीय और प्रौद्योगिक कारक निस्सन्देह बेरोजगारी के कारण हैं, वहाँ यह भी सच है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रकार है दीर्घ कालीन ग्रामीण अल्प बेरोजगारी।

अल्प बेरोजगारी की सीमा

इसका परिमाणात्मक परिमाण प्राप्त करना बड़ा कठिन है और इसकी सीमा अर्थात् तादाद के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री एवम् प्रशासक दोनों का मत ही एक-दूसरे से भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र सच के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के अनेक हिस्सों में, फिलीपीन्स और इण्डोनेशिया के भागों में अतिरिक्त कृषिक आबादी २० से २५ प्रति शत के बीच है। बुचमन (Buchanan) और एलिस (Ellis) के अनुसार भारत में बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी के कारण श्रम के उतने सकल मनुष्य-वर्ष बेकार जा सकते हैं जितने संयुक्त राज्य अमेरिका की समग्र श्रम-शक्ति प्रदत्त करती है। एक सामान्य अनुमान यह है कि घने बसे क्षेत्रों में कुल कृषि उत्पादन में बिना कोई कमी किये सम्भवतः २५ प्रति शत आबादी को कृषि से

हटाया जा सकता है। तृतीय पंच वर्षीय योजना के अनुसार यह सही-सही नहीं बताया जा सकता कि अल्प बेरोजगारी कितनी है। लेकिन अल्प बेरोजगारी का अर्थ यह हो कि वे व्यक्ति जो थोड़ा-बहुत काम तो करते हैं लेकिन और भी काम करने के इच्छुक एवम् करने में समर्थ हैं, तो अनुमान है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या १ करोड़ ५० लाख से १ करोड़ ८० लाख तक है।

अल्प बेरोजगारी के कारण

ग्राम्य क्षेत्रों में अल्प तथा पूर्ण बेरोजगारी साथ-साथ पायी जाती है—दोनों के बीच का अन्तर किसी भी दृष्टि में कोई विशेष नहीं है। गाँवों में बेरोजगारी सामान्यतः अल्प बेरोजगारी का रूप ले लेती है। देश के अनेक भागों में कृषिक मौसम के व्यस्त दिनों में, प्रायः श्रमिकों की कमी पायी जाती है, लेकिन अधिकांश खेतिहर श्रमिकों तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों में लगे श्रमिकों के पाम लगातार काम नहीं रहता। अल्प बेरोजगारी के विभिन्न कारण बताये जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कृषि पर बढ़ती जा रही निर्भरता। सन् १९५१-६१ के बीच के दशक में ७ करोड़ ७० लाख आबादी बढ़ी है। तीसरी पाँचमाला योजना के अनुसार अगले १५ वर्ष की अवधि में श्रम-शक्ति में सात करोड़ नये लोग आ जायेंगे। मोटे तौर पर इनकी बढ़ती कुछ इस प्रकार होगी। तीसरी योजना में डेढ़ करोड़, चौथी योजना में करीब २ करोड़ ३० लाख और पाँचवी योजना में लगभग तीन करोड़। इस जनसंख्या वृद्धि से निश्चय ही अल्प बेरोजगारी की समस्या और भी गम्भीर हो जायेगी। यह भी याद रखना चाहिये कि प्रथम दो योजनाओं में रोजगारी का जो निर्माण हुआ वह गैर-खेतिहर विभाग में हुआ। आगामी योजनाओं में भी यह प्रवृत्ति जारी रहनेवाली है।

श्रमिक-शक्ति को लगातार काम पर लगाये रखने के लिए पूँजी की आम कमी, अल्प बेरोजगारी का एक दूसरा कारण है। जे. राँबिन्सन के अनुसार पूँजी स्रोतों की शिथिलता के फलस्वरूप पूँजी के पिछड़े हुए घने बसे देशों में—और वस्तुतः औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक

विकसित देशों को छोड़ कर सभी जगह—पूर्ण और अल्प बेरोजगारी न एक स्थायी घटना के रूप में प्रकट होती है, बल्कि दीर्घ-कालीन रूप में पायी जाती है। पारीवारिक इकाई के लिए भूमि की पूर्ति सीमित होने की वजह से अल्प बेरोजगारी कृषि की एक दीर्घ-कालीन सगिनी बन जाती है। अल्प बेरोजगारी खेतिहर श्रम में अनवरत निरपेक्ष वृद्धि अथवा उसके आधिक्य और गैर-खेतिहर विभागों का वांछित स्तर तक विकास न होने का फल है। चन्द्र परम्परागत कुटीरोद्योगों की अवन्ति से भी वह बढ़ी है।

आयोजन और रोजगारी

भारत में रोजगारी का सृजन आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। अन्य समस्याओं के समान ही रोजगारी की समस्या दूर करने में जिस बुनियादी कारक से लोहा लेना है वह है विस्तृत आबादी आधार, जिसमें मामूली वृद्धि भी व्यापक रूप वाग्न कर लेनी है। कृषि उत्पादन वृद्धि को तीव्र बनाने और रोजगारी क्षमता में वृद्धि करने के लिए जन-शक्ति स्रोतों का यथा सम्भव परिपूर्ण उपयोग करना, तृतीय योजना का एक प्रधान लक्ष्य स्वीकार किया गया है।

योजना में शामिल कार्यक्रमों में, ग्रामीण जन-शक्ति का उपयोग करने के लिए निर्माण कार्य परियोजनाओं का समावेश एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में—जहाँ पूर्ण और अल्प बेरोजगारी की खाम तौर से अधिकता होती है—पूरक उत्पादक कार्यों में तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक करीब २५ लाख लोगों को रोजगारी प्रदान करना इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। समूचे देश भर में ३६ मार्गदर्शी परियोजनाओं के साथ कार्यक्रम का श्रीगणेश १९६०-६१ में हुआ था।

किसी क्षेत्र में सभी हृष्ट-पुष्ट शरीरवाले और काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए रोजगारी के अवसरों का सृजन तथा यथा सम्भव परिपूर्ण सीमा तक अनुपयोजित जन-शक्ति का उपयोग करना ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम का एक प्रधान उद्देश्य है। यह कार्यक्रम योजना में शामिल किये गये विकास कार्यक्रमों तथा सामुदायिक

विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जानेवाले प्रयामों में मदद देता है और इसलिए यह आवश्यक है कि वह खण्ड विकास योजना का एक महत्वपूर्ण अंग बने। यह कार्यक्रम आवश्यक रूप से ही रोजगारी-प्रधान है। इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम शुरू किये गये हैं, उनमें निश्चय ही सम्बद्ध क्षेत्र की उत्पादक क्षमता और रोजगारी देने की क्षमता में स्थायी योगदान मिलना चाहिये। इस कार्यक्रम के लिए क्षेत्रों का चयन करते वक़्त इस बात का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिये कि उम क्षेत्र में पर्याप्त पूर्ण और अल्प बेरोजगारी है तथा लघु-कालीन कृषिक एवम् अन्य सम्बद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु निश्चित गुंजाइश है। इस कार्यक्रम में भी लोक भागीदारी उसी रूप में आगे आनी चाहिये जिस रूप में वह सामुदायिक विकास तथा अन्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत चलनेवाले कार्यक्रमों में प्राप्त होती है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

किसी निर्माण कार्य का चुनाव करने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि किसी भी एक मद में खर्च ५०,००० रुपये से ज्यादा नहीं होगा और उससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे काम में विस्तृत श्रमिकाई सघटक हो तथा किसी विशेष प्राविधिक कौशल की आवश्यकता न हो और उससे प्रत्यक्ष रोजगारी अधिकतम मिले। ऐसे कामों में सामग्री पर भारी खर्च नहीं होना चाहिये और वे समुचित लघु काल में पूरे होने लायक हों। भू-आरक्षण, मेडबन्दी, नालियाँ बनाने, पानी जमाव को रोकना, लघु मिर्चाई, वृक्षारोपण और भूमि पुनर्वाप्ति जैसे कामों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। कार्यक्रम में ऐसी सम्पत्ति का निर्माण करने की कल्पना है जिस पर स्वामित्व स्थानीय समुदाय का होगा, जैसे, ग्राम तालाब, भत्स्यालय, वृक्षारोपण, चरागाह आदि।

ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत १९६०-६१ में मंसूर राज्य के हिस्से में दो मार्गदर्शी परियोजनाएँ आयी। एक परियोजना तुमकुर जिले के पवागदा में चलायी गयी और दूसरी गुलवर्गा जिले के यादगिरी में।

पवागदा विकास खण्ड गुल्फ पहाड़ी क्षेत्र में है। वहाँ पर वार्षिक वर्षा २० से २२ इंच होती है। चूँकि वर्षा कम और कहीं-कहीं होती है, इसलिए इस क्षेत्र में आये वर्ष सूखे और अकाल पड़ते रहते हैं। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार खण्ड के कुल ९५,५६५ व्यक्तियों में से करीब ७६,००० अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। वर्षा न होने अथवा बहुत कम होने की वजह से कृषकों को शायद ही वर्ष के ३६० दिन काम मिलता हो।

यह अनुमान लगाया जाता है कि कृषकों को अपने खेतों में सामान्यतः वर्ष में चार-पाँच महीने का ही काम रहता है। किसी विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में पूर्ण और अल्प बेरोजगारी कितनी है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन १९६०-६१ में वृष्टि न होने की वजह से समूचा वर्ष ही खाली मौसम का रहा तथा ग्राम्य निर्माण कार्यों से स्थानीय आबादी को राहत मिली, जिसकी बहुत जरूरत थी। पवागदा में परियोजना चालू करने के पीछे मुख्य विचार वहाँ की अभाव-ग्रस्त स्थिति और स्थानीय आबादी को राहत प्रदान करने की आवश्यकता प्रतीत होता है। निर्माण कार्य में शामिल ये दो हजार एकड़ भूमि की मेडबन्दी करना, जिस पर १ लाख ५० हजार रुपये के परिचय्य की बात थी, कोई ४५ हजार रुपये के खर्च से वृक्षारोपण और चरागाहों का विकास करना, वृक्षारोपण के लिए पौधे प्राप्त करने हेतु ५,४०० रुपये के खर्च में पौधशालाओं का विकास, और सामुदायिक कुएँ 'गालने' के लिए २४ हजार रुपये की लागत से लघु सिंचाई कार्य। मई-जून १९६२ के अन्त तक क्षेत्र में परियोजना कार्यों से श्रमिकों को १,२५,६५३ मनुष्य-दिनों के बराबर काम मिला। इनमें काम पर लगे अधिकांश श्रमिक अपनी जीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते थे।

यादगिरी में

मंसूर राज्य में गुलवर्गा जिले के यादगिरी तालुके में दूसरी परियोजना चलायी गयी। चूँकि तालुके में वर्षा केवल २९ इंच ही होती है, इसलिए वहाँ प्रायः सूखे

तथा दुर्भिक्ष की स्थिति रहती है और अकाल की स्थिति में राहत कार्य प्रदान करना वहाँ का एक नियमित कार्य है। लगभग ८० प्रति शत आबादी किसानों की है। चूँकि इस क्षेत्र में पूर्ण और अल्प बेरोजगारी की स्थिति बड़ी भयंकर थी, अतएव मुख्यतः जन-शक्ति खेतों का उपयोग करने के उद्देश्य से वहाँ पर मार्गदर्शी परियोजना चालू की गयी। मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण और लघु सिंचाई तालाबों का पुनरुद्धार तथा भ्रमस्त कार्य हाथ में लिया गया। वृक्षारोपण से ३९,००० मनुष्य-दिनों का काम मिलने का अनुमान है। लघु सिंचाई कार्यों से ३,०८१ व्यक्तियों को काम मिला।

अनुवर्ती वर्षों में उक्त परियोजनाओं का कार्य जारी रहा। इनके अतिरिक्त मैसूर सरकार ने १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के लिए और तेरह परियोजनाएँ द्वितीय क्रम के अन्तर्गत चलाने का निर्णय किया। तृतीय क्रम के अन्तर्गत योजना आयोग ने राज्य को २५ परियोजनाओं का बँटन किया है। वर्ष १९६०-६१ में प्रारम्भ किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत-तृतीय क्रम की २५ परियोजनाओं सहित-अब ४० परियोजनाएँ हैं।

कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन

ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की दृष्टि से खाली मौसम में पूर्ण और अर्द्ध बेरोजगारों को काम प्रदान करते हैं तथा लाभदायक सामुदायिक सम्पत्ति निर्मित करते हैं। देहातो में पूर्ण और अल्प बेरोजगारी की समस्या एक प्रमुख समस्या है। इसका कोई सरल समाधान नहीं है। किसी क्षेत्र में कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पहले के पूर्ण और अर्द्ध बेरोजगारों की संख्या मालूम न होने की वजह से वहाँ पर ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। विकास योजनाओं और ग्राम्य निर्माण कार्यक्रमों से प्राप्त सफलताओं को अलग करके देखना भी बड़ा मुश्किल है।

तीसरी योजना का, उसने रोजगारी के जो अवसर निर्मित किये हैं उनसे सम्बन्धित, मध्य-कालीन मूल्यांकन

कोई उत्साह-वर्द्धक नहीं है। समूची योजनावधि में १ करोड़ ४० लाख नये लोगों के लिए रोजगारी निर्मित करने का लक्ष्यार रखा गया है। उमका ४०-४५ प्रति शत हिस्सा ही पूर्ण हो सका है। मौजूदा सकेतो के अनुसार तीसरी योजना के अन्त तक करीब ४९ लाख लोगों के लिए गैर-खेतिहर क्षेत्र में और १६ लाख के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगारी का निर्माण होगा, जबकि पाँचसाला अवधि के लिए लक्ष्यार क्रमशः १ करोड़ ५ लाख तथा ३५ लाख का था। मूल्यांकन में यह निष्कर्ष भी स्पष्ट हो गया है कि ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम के क्षेत्र में योजनावधि के अन्त में प्राप्त सफलता व्यय की शब्दावली में लक्ष्यार की एक चतुर्थांश और अतिरिक्त रोजगारी के निर्माण के सन्दर्भ में एक-तिहाई होगी। ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च १९६३ के अन्त तक १७६ परियोजनाएँ थी और उन पर परिव्यय हुआ १५ करोड़ रुपये का, जिससे ७६ लाख मनुष्य-दिनों के बराबर अतिरिक्त रोजगारी का निर्माण हुआ।

उक्त तथ्यों से इस बात का पता चलता है कि देहातो की पूर्ण और अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या हल करने में कितनी अन्तर्निहित कठिनाइयाँ हैं। और फिर, जन-संख्या-वृद्धि तथा वैज्ञानिक आधार पर कृषि का वैज्ञानिक ढंग से विस्तार करने पर अतिरिक्त जनसंख्या बढ़ेगी जिसे खाली मौसम के काम की बनिस्बत पूरे समय का काम प्रदान करना होगा। ग्राम्य क्षेत्रों में पूर्ण और अल्प बेरोजगारी की समस्या का स्थायी हल जन-संख्या-वृद्धि पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में हमारी सामर्थ्य पर ही नहीं, बल्कि सर्वव्यापी आधार पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने, ग्रामीण अर्थ-रचना को बहुमुखी और शक्तिशाली बनाने, ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाने, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को वृद्धिशील कस्बाई केन्द्रों के साथ जोड़ने तथा सहकारी आधार पर नये-नये उद्योग चलाने पर भी निर्भर करता है।

मैसूर १४ नवम्बर १९६३

बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में वानस्पतिक सम्पत्ति

सुधांशु कुमार जैन

मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में अनेक प्रकार के पेड़-पौधे पाये जाते हैं। उनके बीज तथा फलो के सग्रह कार्य का सगठन करके और औद्योगिक कामों के लिए उनके उपयोग पर आधारित कुटीरोद्योगों की स्थापना करके लाभदायक रोजगारी प्रदान की जा सकती है।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में रहनेवाले गोण्ड सब से पिछड़े हुए आदिवासियों में से हैं। पिछले चार वर्षों में उनके मध्य जो क्षेत्रीय कार्य किया गया, उससे यह बात सामने आयी है कि अनेक गोण्ड अब भी अपने आस-पास जो वन्य उत्पादन उपलब्ध हैं प्रायः पूर्णतः उन्हीं पर निर्भर हैं।

प्रस्तुत लेख में हम जिले की वानस्पतिक सम्पत्ति अथवा वन्य उत्पादनों पर चर्चा करेंगे। यद्यपि मैंने ऐसे सैकड़ों पेड़-पौधों के सम्बन्ध में मौलिक जानकारी का सग्रह किया है, जिनका आदिवासी भोजन, दवाई रेशे आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं, तथापि, इस लेख में प्रस्तुत सामग्री में वे वन्य उत्पादन आते हैं जिनका सग्रह प्राथमिक तौर पर आदिवासी करते हैं और फिर बाजार में व्यापारियों, ठेकेदारों अथवा किसी सहकारी समिति को उनका विक्रय कर देते हैं। इन उत्पादनों के आधार पर कुटीरोद्योग स्थापित करने की सम्भाव्यता का अध्ययन करना समुचित होगा।

विभिन्न खाद्य उत्पादन, टोकरी, आलात व मोटी बुनाई उत्पादन, तेल, गोद, वर्म शोधन सामग्री तथा अपमार्जक, और अन्य विविध उत्पादनों जैसे विभिन्न उत्पादनों के अनुसार जिले में उपलब्ध पेड़-पौधे भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं। नीचे भिन्न-भिन्न पेड़-पौधों के पहले सामान्य हिन्दी नाम दिये गये हैं और उसके बाद स्थानीय आदिवासियों द्वारा व्यवहार में लाये जानेवाले नाम। अंग्रेजी वानस्पतिक नाम कोष्ठक में दिये गये हैं। तत्पश्चात् पादप का प्रधान उपयोग

बताया गया है, उसके अन्य आर्थिक उपयोग भी संक्षेप में बताये गये हैं।

खाद्य उत्पादन

आमला, इसुरकाया, निल्ली (*emblica officinalis gaerlin f*) बस्तर में ये पेड़ आम तौर पर पाये जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके फलों का उपयोग नहीं किया गया है। काफी बड़ी तादाद में फल नीचे गिरते और बेकार जाते हैं। राय तथा अन्य व्यक्तियों ने हाल ही (१९५७) में खुराक के सम्बन्ध में सर्वेक्षण^१ किया है। उससे पता चलता है कि मध्य भारत में आदिवासियों की खुराक में विटामिन 'सी' की कमी होती है। आमले में विटामिन 'सी' की मात्रा बहुत अधिक होती है। कहा जाता है कि आमले के ताजा रस में विटामिन 'सी' नारंगी के रस से २० गुना ज्यादा होता है। इसलिए आदिवासियों में आमले के उपयोग को लोकप्रिय बनाना चाहिये।

सूखा आमला दवाइयो, केश रजक और केश तेल के लिए उपयोगी होता है, इसलिए उसकी बिन्नी की सम्भावना अच्छी है। आमले के बीज तक आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। आदिवासियों के लिए—खास कर महिलाओं तथा बच्चों के लिए— आमला-सग्रह और प्रशोधन (सुखावन) एक लाभदायक धंधा होना चाहिये।

१ राय, जे के, आर के राव और एस के विश्वास वुलेटिन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एन्थ्रोपोलॉजी, ६ (१)

बैकण्डी, सेनेगड्डा, केकामन, कुलिया पापड (*dosco-rea hispida demist*) इस लता के फल खाद्य हैं। फलों के पतले-पतले कतरे बना कर उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। आदिवासी इन कतरों के 'कुलिया पापड' बनाते हैं और करीब एक रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब में व्यापारियों को बेच देते हैं। यदि इन फलों को सगठित रूप में डकट्टे कर उनके 'कुलिया पापड' बनाये जायें तो अधिक लाभ होगा। पूरक आय के स्रोत के रूप में इस पादप की कृषि तक को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

चिरोजी, आकर, कार, एदका, मोरली सेट्टू, रेका (*buchanania lanzan spr*) इस पेड़ के फल और बीज खाये जाते हैं। बीजों का व्यापार होता है। उनसे खाद्य तेल प्राप्त होता है। आदिवासी बीजों का सग्रह कर माप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को बेच देते हैं। इससे इमारती लकड़ी भी मिलती है और चर्मशोधन सामग्री तथा गोंद भी।

इमली, सिरीटा, सेट्टू, हिटा, हिटग (*tamarindus indica linn*) जिले में यह पेड़ आम तौर पर पाया जाता है। आदिवासी इसके फल तथा लुग्दी का सग्रह कर 'अठवाडियों' में व्यापारियों को बेच देते हैं। इसके फलों में अवलेह होता है, जिसका 'जैम' और 'जेली' तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों से रजक प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि इसके बीजों का यहाँ उपयोग नहीं होता।

तौलूर, बेसेड्डा (*curcuma angustifolia roxb*) इस जड़ी के फलों में खाद्य सत्त होता है, जिसका मिठाई आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे वन विभाग को कुछ राजस्व की प्राप्ति होती है। अगर आदिवासी इसे लगायें तो बैसा करना लाभदायक हो सकता है। इसका सत्त अरारोट जैसा होता है और उसका अच्छा व्यापार होना चाहिये।

टोकरी बनाना, आलात व स्थूल बुनाई

बांस, नेदुर (*dendrocalamus strictus nees bambusa arundinacea rotz*) बांस से टोकरीयों

तथा अन्य ऐसी ही अनेक चीजें बनायी जाती हैं। मियादी की पत्तियों का भी इसमें इस्तेमाल होता है। इस काम का एक लाभदायक धंधे के रूप में सगठन किया जा सकता है।

बोया, टोगा (*cyperus squarrosus*) नालों के किनारे पथरीली जमीन में उगनेवाले मुस्ता का चटाई बनाने में इस्तेमाल होता है।

कुलू, गूदल, हिटम, ईटम, केहला, कोगिरसेट्टू (*sterculia uienis roxb*) इस पादप के रेशों का पानी के 'जग' के विसवाहीकारक के रूप में प्रयोग होता है। (ये पानी भरने के जग अथवा पात्र लोकी व तुम्बी के होते हैं।) कुलू के रेशों मियादी रेशों की सहायता से खोखली तुम्बी या लोकी के चारों ओर जाली बना कर बांध दिये जाते हैं। खेतों में काम करते अथवा गरमियों के दिनों में यात्रा करते वक्त इन पात्रों में पानी ले जाना बहुत सुगम होता है, क्योंकि उन्हें कन्धे पर लटका कर अथवा पीठ पर डाल कर ले जाया जा सकता है और इन पात्रों में स्वयम् में तो सात-आठ औंस वजन होता है, लेकिन उनमें पानी तीन-चार पिण्ड समा सकता है।

यात्रियों और खेतों में काम करनेवालों में, खास कर गरीब लोगों में, पानी लाने-ले जाने के ये पात्र ज्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कीमतवाले जिक के बर्तनों के स्थान पर ये सस्ते पात्र रखना ज्यादा पसन्द करेंगे।

सियादी, कोया, मोहलैन, पवूर, म्याली, मिम्हरखेला (*bauhinia rakhil wt and arm*) इसकी छाल मजबूत आलात और अन्य बहुतेरे कामों के लिए इस्तेमाल में लायी जाती है। आदिवासी इसकी छाल इकट्ठी करके ठेकेदारों को बेच देते हैं। इन ठेकों के जरिये वन विभागों को कुछ राजस्व की प्राप्ति होती है। तने में चर्मशोधन सामग्री होती है और पत्तियाँ बीड़ी बनाने तथा अन्य अनेकों कामों में काम आती हैं।

बस्तर में इसकी बाहुल्यता है और आदिवासी पशुओं के फदे, मछली पकड़ने के जाल आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इस कच्ची सामग्री पर आधारित कुटीर उद्योग का विकास करने के सम्बन्ध में गोज की जानी चाहिये।

उलटकम्बल, आलटी, मरोदफली, नूनीकाया, पिती-लिका, पोटकडी, पोटम, टेइला (*helicteris isona linn*) इसके तने के रेशे में गाय-भैस बँधने के रस्से बनाये जाते हैं व अन्य ऐसे ही कामों में इसका उपयोग होता है। इसके फलों का देशी दवाइयों बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगता है कि अभी तक इस फल का उपयोग नहीं हुआ है।

तेल

मालकँगनी, मनोटिंगा, पापडी, पेग, वादगुल (*celastrus paniculatus wildd*) इस लता के बीजों में प्राप्त तेल का दवाइयों बनाने और रोगनी करने में इस्तेमाल होता है। आदिवासी ये बीज इकट्ठे कर बाजार में व्यापारियों को बेच देते हैं। बस्तर में इस प्रजाति का बाहुल्य है और इसके उपयोग की सम्भावनाएँ होनी चाहिये।

महुआ, गादेग, इपूकमादा, डयुम, इपा, मोडा, तोरा (*madhuca indica gmel*) इस पेड़ से अनेक उपयोगी उत्पादन प्राप्त होते हैं। इसका तेल खाद्य है और रोगनी करने के काम में भी लाया जाता है। आदिवासी काफी तादाद में बीज इकट्ठे करते हैं, उन्हें सुखाने हैं और फिर व्यापारियों को बेच देते हैं।

अरण्डी, जरोण्डा, निरोण्डा (*ricinus communis linn*) यह छोटा-सा पेड़ आदिवासी प्रायः अपने गांवों में लगाते हैं। इसके बीज वे बाजार में बेच देते हैं। बस्तर के उत्तरी हिस्से में आदिवासी पुराने तरीके से इसका तेल निकालते हैं। ओगन, साबुन, केश तेल, स्याही आदि तैयार करने के लिए इस तेल का उपयोग होता है।

कमेल, झापडा, किन्नार, सेडूर, मेन्दूरी (*mallotus-*

philippensis muc-lag) इस पेड़ के बीजों में प्राप्त तेल पण्ट तथा वार्निश तैयार करने के लिए उपयोगी है। फलों से प्राप्त रजक का वस्त्रोद्योग में उपयोग होता है।

कुसुम, कोमिगब (*chleuchera oleosa oken*)

इस पेड़ के बीजों के तेल का दीपक जलाने के लिए उपयोग होता है। इसके अलावा चर्म रोगों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। केश तेल और साबुन बनाने में भी यह काम आता है। आदिवासियों द्वारा इसका संग्रह करने अथवा बेचने के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भेलवा, इदूमरम, जिरमेह, कोहका (*semecarpus anacardium linn f*) फल के बीजकोष से प्राप्त तेल का आयुर्वेदिक मूल्य है। वार्निश आदि बनाने के लिए भी वह उपयोगी है। आदिवासी साप्ताहिक बाजारों में ला कर ये बीज बेचते हैं। जिले में ये पेड़ आम तौर पर पाये जाते हैं और यदि आदिवासियों को कुछ उत्प्रेरणा दी जाय तो बाजार में इनकी उपलब्धि की मात्रा बढ़ सकती है।

गोद

साल, हरगी, सारगी, (*shorea robusta gartn f*) इस पेड़ से प्राप्त गोद पालिश, कार्बन पेपर और वार्निश के लिए उपयोगी होता है। बस्तर में साल के पेड़ काफी मात्रा में पाये जाते हैं। इसके बीजों से प्राप्त तेल रोगनी करने और खाने के लिए उपयोगी होता है।

बीजसाल, बीजा (*pterocarpus marsupium roxb*) इसकी छाल से प्राप्त गोद दवाई के काम आता है। बीजमाल बस्तर के घाट क्षेत्रों में पर्याप्त रूप में पाया जाता है।

कुल्लू (*sterculus wens roxb*) इस पेड़ से प्राप्त करवा नामक गोद का प्रसाधन सामग्री तैयार करने तथा दवाइयों बनाने में इस्तेमाल होता है। दाँतेवाडा की एक सहकारी समिति आदिवासियों में

यह गोद इकट्ठा करती है।

चर्म-शोधन सामग्री तथा परिमार्जक

कर्रा, गर्रादी, ओरममारा, ओरेचट (*cleistanthus collinus benth*) इस पेड़ से प्राप्त चर्मशोधन सामग्री बाहर से आयात की जानेवाली चर्मशोधन सामग्री (वाटल) के समान उपयुक्त समझी जाती है। बस्तर जिले में इन पेड़ों का बाहुल्य है। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक उनके उपयोग की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है।

हरड, हर्रा, काका (*terminalia chebula retz*) बस्तर का यह एक सामान्य पेड़ है। आदिवासी काफी परिमाण में हरड का सग्रह कर व्यापारियों को बेच देते हैं। जिले में छ^२ हरड के कारखाने हैं। इन कारखानों में ४०-५० आदिवासी (प्रधानतः महिलाएँ) काम पाते हैं।

विविध वस्तुएँ

झाड़ू बस्तर के आदिवासी झाड़ू बना कर व्यापारियों अथवा ठेकेदारों को बेचते हैं।

फूल बुहारी (*thysanolaena maxima o'kun-tze*) झाड़ू बनाने में यह घास बहुत काम आती है। इसकी बनी झाड़ुओं के ट्रक के ट्रक बाहर अन्य स्थानों को भेजे जाते हैं। निम्न उपादानों से बनी झाड़ुएँ भी आदिवासी महिलाएँ जगदलपुर, धोदई आदि स्थानों के साप्ताहिक बाजारों में बेचती हैं।

चिन्दा, घिण्डी, इण्डी, इटेसेट्टू, इटेगड्डा (*phoenix acaulis roxb*) बस्तर जिले में यह छोटा ताड़ पर्याप्त रूप में मिलता है। झाड़ू बनाने और घरों की छत छाने में इसका काफी प्रयोग होता है।

ढेकना, नाडक (*desmodium pulchellum benth*) इसकी टहनियों की झाड़ू बनायी जाती है।

लटकनी, टोटाटुण्डे, गुड्डनटालू (*desmodium latifolium dc*) इसकी टहनियों भी झाड़ू के इष्टे बनाने के काम आती हैं।

कघे स्थानीय रूप से बनाया गया कघा पास में रखना महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए ही एक गर्व की वस्तु है। युवक व युवनियाँ कघे पर छोटी-छोटी हड्डियों चिपका कर अथवा ताड़ गेशे से सुन्दर बुनी हुई डिजाइनवाले कघे रखना पसन्द करती हैं। ये कघे (जिन्हें स्थानीय रूप से पनिया, पडिया, कहा जाता है) सामान्यतः इन पादपों से बनाये जाते हैं महुआ (*madhuca indica gmel*), पालो, कुदै (*holarrhena antidysenterica wall*) और पाखना कुर्ल, कालमोदिया, मोदिया, कर्ज, कालूइद्गम, राजनिस (*gardenia latifolia wil*)।

एल्विन^३ ने कई तरह के कघों का वर्णन किया है और उदाहरण दिये हैं। वृद्धा महिलाएँ तो अब तक काठ की कधियों का इस्तेमाल करती हैं। हाथ बने सुन्दर-सुन्दर कघों को बड़ी अच्छी चीज के रूप में बेचा जा सकता है।

तम्बाकूदानी जिस प्रकार सभी महिलाएँ और लड़कियाँ तथा युवक अपने पास कघे रखते हैं वैसे ही तम्बाकूदानी (स्थानीय बोलचाल की भाषा में जिसे चिनौती, पोगागेटा कहते हैं) सभी पुरुषों के पास मिलेगी—विशेष कर उन प्रौढ़ों के पास जो धूम्रपान करने के स्थान पर 'खैनी' के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। विविध आकार-प्रकार की तम्बाकूदानियाँ उपलब्ध हैं। सामान्य गरीब आदिवासी एक बास की थोथी पोरी से काम चला सकता है तो कोई बहुत ही सुन्दर तम्बाकूदानी भी रखेगा, जो नक्कासी आदि के द्वारा खूबसूरत व डिजाइनदार बनायी हुई होती है।

ये तम्बाकूदानियाँ सामान्यतः उन पादपों के काठ से

२. 'पोकेट कम्पेडियम ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिक्स,' बस्तर, १९५८-५९।

३. एल्विन, वी 'नि ट्रायबल आर्ट ऑफ मिडल इण्डिया,' १९५९।

बनायी जाती है जिनका कच्चे बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सिवना, गोटा, कुर्सी, कुसुमरम (*cmelina arborea 10xb*) से भी ये बनायी जाती है।

मोडे, दुम्पीडो, गरियुम, केकड (*lannea corio-mandeluca meir*) कच्चे और तम्बाकूदानी यहाँ की खरीद कर लायी जानेवाली, खास कर निम्न तथा मध्यम आय वर्गवाले खरीदारों के लिए, अच्छी चीजे हैं।

बीडी के पत्ते

तेन्दू (*diospyros melanoxylon roxb*) तेन्दू के पत्तों का सग्रह प्रधानतः बीडी बनाने के लिए होता है।

उक्त अधिकांश चीजों का फिलहाल किसी हद तक असंगठित सग्रहकर्त्ताओं के जरिये उपयोग होता है। सन् १९५९ से सम्बन्धित आकड़ों से पता चलता है कि जिले की लगभग दस लाख आबादी में से केवल १५० व्यक्ति ही औद्योगिक कामों में लगे हुए हैं। बीडी, बर्रा, चावल, तेल और आटा पिसाई ही मुख्य उद्योग हैं। निम्न तालिका उद्योगों सम्बन्धी आकड़े प्रस्तुत करती है। सभी औद्योगिक इकाइयों चार

शहरों—जगदलपुर, कोंकर, चरमा और कोण्डागॉव—में अवस्थित हैं।

उद्योग	इकाई	दैनिक औसत रोजगारी		
		संख्या	पुरुष	महिलाएँ योग
बीडी	८	३२	१७	४९
हर्रा	६	३	४०	४३
चावल	२	१२	१५	२७
तेल	३	७	७	१४
आटा पिसाई	५	११	५	१६

निम्न की सम्भाव्यता का पता लगाना अच्छा होगा (१) उक्त स्रोतों पर आधारित कुटीर उद्योग, और (२) बिचवानियों को कम करते हुए वन्य उत्पादनों के सग्रह कार्य का संगठन।

आदिवासी साप्ताहिक बाजारों से साबुन, केश तेल, रोशनी के लिए तेल, बीडी तथा चर्मोद्योगी सामान खरीद कर लाते हैं। इन चीजों के उत्पादन के लिए अधिकांश कच्ची सामग्री आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध है।

कलकत्ता २७ फरवरी १९६४

इसलिए मैं एक विश्व के सान्निध्य में आस्था रखता हूँ और मेरा विश्वास है कि मानव जीवन फिर से अपने समस्त पहलुओं एवम् कार्यों में एक रूप बनने जा रहा है। मेरा यह भी मत है कि धर्म के क्षेत्र में संगोपन प्रवृत्ति विश्व व्यापकता की प्रवृत्ति के आधीन, राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रवाद विश्व सत्ता के आधीन; और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता मानव जीवन के विस्तृत दृष्टिकोण के आधीन होने जा रही है।

— अर्नाल्ड जे. टायनबी जेनरल एट सेवण्टी फाइव ।

सूक्ष्म प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान

भारतानन्द

देश में बेरोजगारी की विकट समस्या का समाधान ऐसे ही उद्योगों से सम्भव है, जिनमें काम करनेवाले प्रति व्यक्ति के हिस्से से औसत पूँजी विनियोजन कम तथा राजगारी की शक्यता अधिक हो और जिन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ चलाया जा सके।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सेवा-प्रधान मार्बजनिक् क्षेत्र तथा मुताफे-प्रधान निजी क्षेत्र में विभाजन की शुरुआत, अपवाद स्वरूप कुछ मिश्रित सहयोगों को छोड़ कर, पश्चिमी आर्थिक विचारधारा से हुई है। भारत के आर्थिक यथार्थ से उसका कोई मेल नहीं है। भारत में एक 'जीवन-प्रधान' सामाजिक क्षेत्र भी मौजूद है, जो अपने काम (सेल्फ-इम्प्लायमेंट) के ढाँचे में सन्निहित है। वर्तमान में उसे न तो मान्यता मिली है और न उसकी व्याख्या ही हो पायी है और एक बड़ी भूल की वजह से वह निजी क्षेत्र के साथ मिलाजुला है, फिर भी इतना जरूर है कि अपनी समस्त विशेषताओं तथा उच्चरित लक्षणों एवम् आवश्यकताओं सहित वह महज मौजूद ही नहीं है, बल्कि उसके दायरे में आनेवाले लोगों की संख्या तथा राष्ट्रीय आय में उसके हिस्से को देखते हुए देश की अर्थ-व्यवस्था का वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

तीसरा क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र के दायरे में वे सब लोग आते हैं, जो अपने औजार तथा वक्त के मालिक हैं, कच्चे माल तथा बाजारों तक जिनकी सीधी पहुँच है और स्वयम् मालिक तथा कामगार, मरमायेदार तथा काम करने-वाले, प्रबंधक तथा मजदूर बनने के लिए जिनके पास पर्याप्त पूँजी व तकनीकी जानकारी है। इनमें स्वतंत्र किसान, छोटे कारीगर तथा व्यापारी, छोटे ठेकेदार तथा कारखानेवाले लोगो का विशाल वर्ग शामिल है, जो अकेले

या अपने परिवार के साथ या छोटी हिस्सेदारी, मजदूरों की छोटी जमान या उत्पादक-महकार के बगैर काम करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र राज्य अधिकृत पूँजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है और निजी क्षेत्र का मतलब है राज्य नियंत्रित पूँजीवाद। सच्चा जनतांत्रिक समाजवाद सिर्फ तीसरे क्षेत्र, 'अपना काम' से ही सम्भव है। सार्वजनिक क्षेत्र 'जनतांत्रिक' नहीं हो सकता और न निजी क्षेत्र 'समाजवादी' ही बन सकता है। न्यासिता, जो समस्त तीनों क्षेत्रों को एक में समग्रित करेगी और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समष्टि की भलाई के लिए सचेत होकर और जी भर काम करेगा, आशा से अधिक आदर्शवादी है।

महज सर्वांगीण आर्थिक विकास समृद्धिशाली औसत का सांख्यिकीय भ्रम पैदा कर सकता है। उसमें उच्च आय का विस्तार होता है और निम्न आय का अन्तर्भवन, किन्तु वह धीमी और बेकार की प्रक्रिया है। सही सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन में प्रत्यक्ष भाग लेना तथा उत्पादित वस्तुओं के आवश्यकतानुसार तत्काल प्राप्ति मुनिश्चित होनी चाहिये।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, अपने सफल मंचालन के परिणाम-स्वरूप समाज के अंदर विभिन्न स्तर बनाते हैं तथा वर्गों का निर्माण करते हैं। इन स्तरों का निर्माण उनकी कार्य-प्रणाली के कारण होता है या आय अथवा दोनों की वजह से, कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि तथ्य

यह है कि एक नियंत्रण करनेवाले तथा व्यवस्थापकीय वर्ग का निर्माण होता है, जिसकी हरकतें और जीवन-यापन के स्तर अपने होते हैं और किसानों तथा मजदूरों के विशाल समूह में उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। एक समाजवादी समाज—जिसमें स्तर, आय और अवसर की वास्तविक समानता उपलब्ध हो—सिर्फ अपने काम से ही सम्भव है।

भारत के विशाल तथा हरदम वृद्धिशील और नश्वर जनबल की समस्याओं को हल चाहिये, जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र नहीं दे सकते। बड़े-बड़े कल-कारखाने बना कर बेकारी के कठिन अवरोधों का अंत नहीं कर सकते। आधुनिक उद्योग उच्च पूँजी विनियोजन और न्यून श्रम-शक्त्यता पर जोर देते हैं, जबकि भारत में ठीक इसकी विपरीत अवस्था की जरूरत है उच्च श्रम-शक्त्यता तथा औसतन प्रति कर्मि कम पूँजी का विनियोजन। यहाँ आवश्यकता है इस बात की कि अधिकाधिक लोगों के लिए उत्पादक और लाभकारी रोजगारी की व्यवस्था की जाय, किन्तु उसमें शेष बेरोजगार लोगों की रोजगारी की शक्त्यता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिये। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो तत्काल, प्रत्यक्ष और उपयुक्त पैमाने पर किया जा सकता है। यह हो सकता है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की खाई को पाटने से और शक्त्यतापूर्ण, किन्तु साधनहीन उपभोक्ता को उत्पादन करने तथा पूर्ण शक्य, किन्तु बेरोजगार उत्पादक को उपभोग करने में समर्थ बना कर उस खाई को विलुप्तप्राय स्थिति में लाने से।

‘अपना काम’

अपने काम का प्रथम उद्देश्य होगा परिवार के अंदर स्वावलंबन, तब गाँव का समाज, फिर पड़ोसी गाँव की सेवा। उसके बाद तालुका, फिर जिला, तब किसी खास इलाके में प्राप्त प्राकृतिक साधन और स्थानीय कौशल के विशेष सामर्थ्य में अखिल भारतीय स्तर पर माँगों की पूर्ति।

इसमें जोर दिया जाता है उपभोक्ताओं की प्राथमिक

आवश्यकताओं तथा मुविधाओं पर, दूर के साधनों में उसकी यथा सम्भव आजादी पर, उत्पादक और उपभोक्ता के नजदीकी सम्पर्क पर नहीं, उसके व्यक्तिगत सम्पर्क पर, स्थानीय कच्चे माल, कौशल तथा बाजार की निश्चितता पर तथा सृजनात्मक प्रयासों को उत्पादन तथा वितरण के विकेन्द्रित, स्वयं गतिशील, स्वयं निर्देशित तथा स्वयं सुधारक केन्द्रों की शक्ति देने पर।

रोजगारी का स्वरूप

पूर्ण तथा आंशिक बेरोजगारी की वजह से रोजाना बर्बाद जानेवाले श्रम-दिनों की तादाद करोड़ों में गिनी जा सकती है और किसी-किसी मौसम में तो वह आसानी से १० करोड़ तक पहुँच जाती है। ऐसे लोग जीवित हैं, पर बेकार बैठे हैं, वे खाते हैं, पर कुछ उत्पादन नहीं करते। भोजन-वस्त्र के लिए वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं और इस प्रकार वे दूसरों के जीवन-स्तर को नीचा करते हैं। बेकारी पर दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। उसका ताल्लुक सिर्फ इसी बात से नहीं होता कि रोजाना आठ घंटे और साल में २०० रोज काम किया जाय, बल्कि उसका अर्थ होता है मनुष्य की समस्त आवश्यकताएँ—भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक—पूरी करने के लिए पर्याप्त कमाई भी।

इसका एक तीसरा दृष्टिकोण भी है। अगर कोई कर्मचारी किसी खास मजदूरी के बदले किसी काम पर लगा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सारी कुशलताएँ, योग्यताएँ और रुचि भी उसमें लगी है। ऐसी अवस्था में उसे समग्र रूप से काम पर लगा हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समग्र रोजगारी का अर्थ सिर्फ प्राप्य काम के समय और शक्ति का पूर्ण उपयोग ही नहीं होता, बल्कि भारत की विशाल और सुयोग्य आबादी के अनेक और विभिन्न कौशल, प्रतिभा तथा गुण को व्यवहार में लाना भी होता है, जिनकी अब तक न तो खोज की गयी है और न जिनको उपयोग में ही लाया गया है। हमारे शब्दों में, रोजगारी का मतलब है, व्यक्ति विशेष के जन्मजात तथा सीखे हुए गुणों में

अनिवार्य रूप में उपयोग में लाना। उसमें व्यक्ति की प्रेरणा, उत्साह, कल्पना, खोज करने की प्रवृत्ति, साधन-सम्पन्नता, धैर्य तथा उसकी समस्त प्रतिभा, कौशल तथा ज्ञान को भी अवश्य अवसर मिलना चाहिये। संयोगवश, समग्र रोजगारी पूँजी की आवश्यकता या उत्पादन-व्यय को कम करती है, लोगों के पुनर्वास के साथ ही वह उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाती है।

‘अपने काम’ का क्षेत्र

‘अपने काम’ को लाभकारी ढंग से चलाने के लिए परिवार ही सब से छोटी इकाई है। वह स्वाभाविक तौर पर एक बहुदेशीय सहकार है। जिस किसी धंधे को वह करता होता है, जब कभी उसमें अधिक लोगों के सहभागी होने की आवश्यकता होती है, तो छोटी साझेदारी और उत्पादक-सहकार का निर्माण होता है। पर मजदूरी के बदले अपना समय और श्रम बेचनेवाले समस्त व्यक्ति मजदूरी-रोजगारी करनेवाले होते हैं, अपना काम करनेवाले नहीं, भले ही उन्हें काम देनेवाली संस्था सहकारी ही क्यों न हो। (ऐसी सहकारी संस्था, जिसमें सदस्य काम करनेवाले नहीं होते या काम करनेवाले सदस्य नहीं होते, सामाजिक क्षेत्र की नहीं होती।) यह स्पष्ट है कि अपने काम के ढाँचे का उत्पादन—जिसका आधार प्राथमिक तौर पर स्थानीय कच्चा माल तथा परिवार एवं पड़ोस में रहनेवालों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो—श्रम, साधन, सामग्री, व्यवस्था और परिवहन के मामले में सर्वाधिक किफायती हो सकता है।

अपने काम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, उसकी लचक और लोच में। अपना काम तथा स्वयं में पूर्ण छोटी सामाजिक इकाइयों, अन्य किसी तरह के आर्थिक संगठनों की तुलना में ज्यादा आसानी से परिवर्तनों को ग्रहण कर सकती है। अपने काम के क्षेत्र में आम प्रौद्योगिकी का स्तर विशिष्ट तथा स्व-चलित कारखानों की तुलना में निम्न हो सकता है, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता की निम्न उत्पादकता की तुलना में पूँजी की लागत भी कम होती है, खर्च कम होता है और सामाजिक लागत भी न्यून होती

है। आर्थिक समस्या साधारण और आसान हो जाती है और सामाजिक सम्पर्क परस्पर आर्थिक निर्भरता से दूर हट कर उच्च भावात्मक तथा बौद्धिक स्तर पर केन्द्रित हो जाता है।

अपना काम व्यक्ति विशेष के रोज-रोज के विवेचन, मूल्यांकन तथा रुचि को प्रशिक्षित करता है और उसे बड़ी जिम्मेदारियाँ लेने तथा दक्षतापूर्वक और विश्वास के साथ उन्हें सम्भालने की योग्यता प्रदान करता है। वह हमें स्वयं नियमित समाज की स्थापना की ओर ले जाता है, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा आर्थिक सत्ताएँ उसी में समाहित होती हैं और जिसमें व्यक्ति आकांक्षित स्वयं निर्मित, स्वयं निदेशित तथा स्वयं नियंत्रित होता है।

राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण जरिया

भारत की ८० प्रति शत से अधिक आबादी गाँवों में रहती है और ७० प्रति शत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ की कुल श्रम शक्ति का ७२ प्रति शत अपना काम करता है। (अपना काम करनेवालों में कृषिक रोजगारी के ८० प्रति शत तथा गैर कृषिक के ५५ प्रति शत लोग हैं)। अपने काम का क्षेत्र भारत में सिर्फ सब से बड़ा रोजगार देनेवाला ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आय का वह सब से बड़ा अकेला स्रोत भी है। सामाजिक क्षेत्र को मान्यता न मिलने की वजह से सही आकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं, पर अंदाज है कि अपना काम करनेवाले लोगों की आय, उसी श्रेणी (किसान, पशु-पालक, कारीगर और शिल्पकार, छोटे ठेकेदार तथा व्यापारी एवं डाक्टर, वकील, कलाकार तथा सीने कलाकार आदि समान श्रेणी में आते हैं।) के प्रति कामगार से कम नहीं है, और वह भारत की राष्ट्रीय आय के ५० प्रति शत से अधिक है।

अपना काम, भारत में प्रभावशाली रोजगारी का तरीका है। उसको परिचय की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसके सही संगठन तथा अधिक विकास के लिए सिर्फ मान्यता की जरूरत है। मौजूदा समय में भारत में

अपना काम न तो पूर्ण है और न समग्र ही। साथ-साथ प्रति मनुष्य-दिन उसकी उत्पादकता भी इतनी पर्याप्त नहीं है कि उसकी आवश्यकताएँ पूरी कर सके और विकास-पूँजी का निर्माण कर सके। एक बार सर्वाधिक जनसंख्यावाला और उत्पादक क्षेत्र होने की मान्यता मिल जाने के बाद तीनों क्षेत्रों—सार्वजनिक, निजी तथा सामाजिक—के अलग-अलग दायरे सुनिश्चित हो कर उसे भी पर्याप्त सरक्षण, वित्तीय, तकनीकी तथा व्यापारिक सहायता मिलने लगेगी।

विनष्ट होने का खतरा

मौजूदा समय में अपने अस्तित्व और मूल्य की मान्यता के अभाव में 'अपना काम क्षेत्र' के समक्ष धीरे-धीरे विनष्ट होने का खतरा उपस्थित हो गया है। उच्च स्तरीय उत्पादकता तथा तीव्र रूप से विकासशील सामूहिक औद्योगिकी की तत्काल आवश्यकता की वजह से एक ऐसी स्थिति आती है, जिसमें देश का उत्पादन बढ़ता जाता है, पर रोजगारी में उसके अनुकूल वृद्धि नहीं हो पाती, देश अधिक से अधिक वस्तुएँ बनाने लगाता है, पर कम से कम लोगों को काम दे पाता है, जिसका अनिवार्य परिणाम होता है विपुलता के बीच दरिद्रता। एक तरफ ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ और दूसरी तरफ फटेहाल झोपडियाँ, प्रायः समस्त विकासशील देशों का स्वरूप बन गया है।

अपना काम या सामाजिक क्षेत्र को मान्यता तथा पुनर्वास का कोई भी कार्यक्रम उसकी जिव्यता तथा सहज शक्ति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। रोजगारी प्रदान कर सकने की विशाल शक्त को विशिष्ट गुण की वजह से प्रतिक्रियाओं का एक वास्तविक मिलमिला शुरू हो जाता है। अपने काम में रोजगारी के साथ ही बाजार का भी निर्माण होता जाता है, उत्पादक स्वयं ही अपनी उत्पादित वस्तुओं का उपभोक्ता होता जाता है, और इस प्रकार बाजारों में बहुलता नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति विशेष की उत्पादक-क्षमताएँ कम होती

हैं और वे सिर्फ स्थानीय बाजारों के लिए ही उत्पादन करते हैं।

आबादी की वृद्धि के साथ-साथ वकारा भी बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय आयोजन से सम्बन्धित लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि औद्योगिक विकास, चाहे वह कल्पना की कितनी भी उड़ान क्यों न भरे, सामान्य आबादी वृद्धि को ही नहीं सम्भाल सकता, बेकारों के विशाल समूह को काम में लगाने की बात तो दूर रही। इसका तात्कालिक समाधान तो सिर्फ समुचित निर्देशित और सहायता प्राप्त 'अपना काम' ही कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रेरणा, उत्साह, क्षमता और धैर्य को सगठित करना चाहिये, ताकि बेकारी की जड़ पर प्रहार करने योग्य शक्ति उत्पन्न की जा सके।

विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग

तीनों क्षेत्रों के बीच उत्पादन की जिम्मेवारी के वितरण की समस्या का समाधान, कुछ हद तक उनके स्वभाव से ही हो जाता है। सार्वजनिक या राज्य क्षेत्र में आते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा तथा अखंडता एवं देश की आर्थिक व्यवस्था को सुगम बनाये रखने के लिए अनिवार्य सारे उद्योग—जैसे प्रतिरक्षात्मक उद्योग, यातायात और संचार, मिर्चाई और बिजली, बुनियादी कच्चे माल और अनिवार्य सेवाएँ तथा आम तौर पर ऐसे उद्योग जिन्हें एकाधिकार या प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखने की आवश्यकता है।

निजी क्षेत्र, सामाजिक या आर्थिक तौर पर चाहे किनना भी उपयुक्त क्यों न हो, मुख्यतः मुनाफा-प्रधान होता है। उसका असली क्षेत्र है उद्योग, जहाँ प्रतिस्पर्धा या अन्य कारणों से अनिश्चितता की स्थिति तथा जोखिम मौजूद रहती है। ऐसे निजी उद्योगों का, जिनमें कोई जोखिम न हो, स्थायित्व की स्थिति आ जाने के बाद उनके मरथापकों और हिस्सेदारों को अच्छा पुरस्कार दे वर राष्ट्रीयकरण या सामाजीकरण हो जाना चाहिये।

सामाजिक क्षेत्र का दायरा, उसके स्वभाव से ही सुनिश्चित होता है। वह प्रत्यक्ष खरीदारों के विशाल

समाज का पोषण करता है। सगठन के सिर्फ दो ही तरीके हैं जिनमें 'अपना काम' चल सकता है। परिवार तथा छोटी मिलीजुली हिस्सेदारी या उत्पादक सहकारी समिति। इनमें से प्रत्येक, क्षेत्रीय आर्थिक सत्ता के संरक्षण और निर्देशन में काम करता है। यह क्षेत्रीय आर्थिक सत्ता सामान्यतः बहुदृष्टीय सेवा सहकारी समिति के रूप में होती है। पंजीगत लागत तथा उत्पादन इकाई का आकार छोटा एवं उत्पादन का तरीका सरल और सीधा होता है। अपने काम के लिए कोई उद्योग नहीं उपयुक्त समझा जा सकता है, जब (१) प्रति मालिक से उसके कर्मचारियों की औसत संख्या कम हो, और (२) उसमें लगे हुए लोगों में अधिकांश स्वतंत्र काम करनेवाले कार्यकर्ता हों।

अपने काम का अनुपात

'नीचे से निर्माण' ('बिल्डिंग फ्रॉम बिलों'—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, १९५५) में उद्योगों के ७९ समूहों की जाच की गयी और यह देखा गया कि ५५ प्रति शत उद्योगों के कुल रोजगार पानेवालों में अपना काम करनेवालों की तादाद ३५ से ८५ प्रति शत तक थी, १५ प्रति शत उद्योगों में अपना काम करनेवाले ७० से ८५ प्रति शत, २७ प्रति शत उद्योगों में ५० से ७० प्रति शत तथा १३ प्रति शत उद्योगों में ३५ से ५० प्रति शत थे। दूसरे शब्दों में, भारत के मौजूदा उद्योगों में आधे उद्योग 'अपने काम' के उपयुक्त हैं, पर ४२ प्रति शत ज्यादा उपयुक्त हैं, क्योंकि उनमें काम करनेवाले स्वतंत्र कर्मचारी, विभिन्न कठिनाइयों और रुकावटों के बावजूद, उनमें लगे कुल लोगों की तादाद के ५० से ८५ प्रति शत तक है। अधिकांश उद्योगों में मालिकों की तुलना में कर्मचारियों का अनुपात लगभग १:१ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश उद्योग औसतन कम श्रम-शक्ति में चलते हैं और ऐसी अवस्था में उन्हें आसानी के साथ परिवार और छोटी हिस्सेदारी या सहकारिता के लिए सुरक्षित किया जा सकता है।

मजदूरी-रोजगारी की स्थिति से अपने कामवाली रोजगारी पर जाना सामाजिक क्षेत्र को मिलनेवाली वित्तीय, सगठनात्मक तथा तकनीकी सहायता की पूर्णता पर निर्भर करेगा। निःसंदेह रूप से कृषि तथा कृषि पर आधारित समस्त उद्योग अपने काम के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। अन्य उद्योगों में, प्राथमिक आवश्यकता की समस्त वस्तुएँ, जैसे खाद्य, वस्त्र तथा आवास आदि, जो एकाधिकार के बराबर होंगी सामाजिक क्षेत्र को मिलनी चाहिये। (यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सामाजिक क्षेत्र की दक्षता को उसके मौजूदा कार्य में नहीं आकना चाहिये, क्योंकि वह इस समय निश्चित रूप से बहुत ही निम्न स्तर की है। उसे उसकी उत्पादन और रोजगारी की विगल शक्तों के आधार पर आकने की कोशिश की जानी चाहिये।)

सब से निम्न स्तरवालों की मदद

दारिद्र्य से ऊपर के स्तर की जिन्दगी बमर करने के लिए विवेचन के बाद स्थिर किया गया है कि पाँच सदस्यों के एक परिवार के लिए कम से कम तीन हजार रुपये की सालाना जरूरत पड़ेगी। यह आँकड़ा कम नहीं हुआ है, बल्कि काफी बढ़ गया है। किन्तु चूँकि आबादी की प्रति व्यक्ति औसत आय ज्यादा नहीं बढ़ी है और न्यूनतम आवश्यकता की आधी से भी कम है, सालाना ३,००० रुपये का आँकड़ा अत्यधिक कल्पनात्मक है और उसे यों ही रहने दिया जा सकता है। इससे भी बदतर हालत तो यह है कि ५० प्रति शत से अधिक भारतीय परिवार इस औसत का महज एक अंश ही कमा पाते हैं। सामाजिक क्षेत्र के मुनियोजित विकास में सब से कम वार्षिक आयवाले परिवारों पर सब से पहले ध्यान देना चाहिये फिर ऊँची आयवालों पर और यह क्रम तब तक जारी रहे, जब तक सब लोग ३,००० रुपये सालाना आय के स्तर तक न पहुँच जायें। प्रत्येक स्तर पर पुनर्वास की लागत विभिन्न होगी, निम्न-तर स्तर पर सब में कम और उच्चतर स्तर पर सब में अधिक। भारत के प्रत्येक परिवार को ३,००० रुपये

वापिक आय के स्तर पर लाने के सम्बन्ध में अनुमान लगाना आसान न होगा, किन्तु इसमें कोई सदेह नहीं कि अपना काम उसका एक हल उपस्थित करता है और वह सब से सस्ता और सब से जल्दी होनेवाला भी है।

सामाजिक क्षेत्र के स्थिरीकरण तथा विस्तार के मार्ग में सब से बड़ी एकमात्र रुकावट है उसकी प्रौद्योगिक हीनता। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने एकमात्र बड़े आकार तथा बड़े पैमाने की औद्योगिक जटिलताओं पर ही अपने को केन्द्रित रखा है और आधुनिक यंत्र-औजार तथा उत्पादन मशीनें और भी बड़ी पेचीदी तथा कीमती बनती जा रही हैं। स्वभावतः अपना काम करनेवाले परिवारों या छोटे सहकारों की क्रय-शक्ति इतनी नहीं है कि वे उन्हें प्राप्त कर सकें। इसके अलावा स्थानीय बाजारों की सीमित आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी उत्पादन क्षमता भी काफी अधिक है।

ऐसी अवस्था में आवश्यकता है सामाजिक क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा कार्यों के लिए उपयुक्त नयी प्रौद्योगिकी की, जिसे सूक्ष्म प्रौद्योगिकी (छोटी प्रौद्योगिकी) कहा जा सकता है। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, सम्बोध तथा रूपाकन, दोनों दृष्टियों से पूर्णतः आधुनिक है और सर्वाधिक आधुनिक अनुमानों तथा विकास के तत्वों का उसमें समावेश है। छुटाई, सरलता तथा सस्तेपन को दृष्टिगत रखते हुए उसका रूपाकन किया गया है। किसी भी तरह उसमें गुणों का त्याग नहीं किया गया है।

अपना कामवाली एक सामाजिक इकाई—चाहे वह परिवार हो, सहकारी समिति हो या गाँव—की तुलना एक अतरीक्ष यान के साथ की जा सकती है। जिस प्रकार एक अतरीक्ष यान अपने छोटे से दायरे में, सीमित वजन और मात्रा में असाधारण तौर पर सम्बेदनशील और जटिल यंत्रों के समूह को लेकर ऊपर उड़ता है, उसी प्रकार अपने कामवाली एक इकाई में सीमित पूँजी, श्रम-शक्ति तथा उत्पादन-शक्ति के अंदर उत्पादन के लिए आवश्यक समस्त वस्तुएँ मौजूद होनी चाहिये।

सूक्ष्म प्रौद्योगिकी मौजूद है। सिलार्ड मशीनें, टाइप

राइटर, स्कूटर, धुलाई मशीनें, रिफ्रिजरेटर, एयर-कंडिशनर, ट्रांजिस्टर रेडियो, पोर्टेबल टेलीविजन सेट तथा टेप-रेकार्डर आदि उच्च स्तरीय सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं। ये सब छोटे, मजबूत तथा औसतन मस्ते यंत्र हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादक यंत्रों के सम्बन्ध में भी यही विधि अपनायी जाय और समस्त प्रकार की आवश्यक अच्छी, मजबूत, टिकाऊ और मस्ती छोटी मशीनें बनायी जाय।

फिर यह भी स्थिति है कि इस तरह की छोटी-छोटी औद्योगिक मशीनें तथा यंत्र भी मौजूद हैं। घरेलू कारखाने, प्रयोगशालाएँ, औपव बनानेवाले कारखाने, सूक्ष्मास्त्र बनानेवाले कारखाने तथा आम तौर पर जहाँ उत्पादन का उच्च मूल्य लघु स्तरीय उत्पादन से जुड़ा हुआ है, आदि के लिए उन मशीनों या यंत्रों का प्रयोग होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उन छोटी मशीनों का विस्तार उन क्षेत्रों में किया जाय, जो मौजूदा समय में ऊँचे स्तर के उद्योग लिये बैठे हैं। बड़े कारखाने दूर के स्थानों से कच्चे मालों की सम्प्राप्ति करें और तैयार माल को दूर-दूर के बाजारों में भेजें, उनके बदले सामाजिक क्षेत्र को काफी तादाद में 'सूक्ष्म-यंत्र' देने की आवश्यकता है, ताकि वे स्थानीय बाजारों के लिए, मुख्यतः स्थानीय कच्चे माल का प्रशोधन करें।

ऐसे 'सूक्ष्मकृत यंत्र' बड़े कारखानों में सामूहिक रूप से तैयार किये जा सकते हैं। सामूहिक पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन के बदले सूक्ष्म यंत्र का सामूहिक उत्पादन हमें करना चाहिये, ताकि घर पर वस्तुएँ तैयार कर सकें। कौन-सी प्रौद्योगिकी ज्यादा लाभकारी होगी, बड़ी या छोटी, इस प्रश्न के सामने आते ही जवाबी सवाल उठता है, लाभकारी किस के लिए। सामूहिक उत्पादन की सुविधाएँ, एक बार स्थापित हो जाने के बाद किसी खास क्षेत्र में अस्थायी या स्थायी तौर पर आगिक या सम्पूर्ण एकाधिकार कायम कर लेती हैं और उनका लाभ निश्चित रूप से उद्योग के मालिकों को पहुँचता है, चाहे वे हिस्सेदार हो या राज्य। किन्तु उनके

उत्पादन की लागत में जब उगार और मुताफा प्रधान उत्पादन पद्धति से उत्पन्न आबादी के अधिकांश लोगों की बेकारी तथा निम्नतम स्तर के जीवन-यापन की विशाल सामाजिक और आर्थिक लागत भी जोड़ दी जाती है, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपना काम प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुएँ सब से कम मूल्य पर दे सकता है।

यह बात अच्छी तरह साबित की जा सकती है कि पर्याप्त संरक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी के लाभ प्राप्त करने के बाद सामाजिक क्षेत्र सब तरह से बड़े कारखानों का मुकाबला कर सकता है। किन्तु मुख्य बात यह नहीं है। सबसे बड़ा तथ्य तो यह है कि 'अपना काम' भारत के समस्त बेकार नर-नारियों को महज रूप में, आसानी से और अविलम्ब काम दे सकता है और जैसा-जैसे उसके संगठन की गति बढ़ती जायगी, अपना बाजार और पूँजी वह स्वयं निर्मित कर लेगा।

गाँवों के लिए शक्ति

सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की उत्पादक-क्षमता सीमित हो सकती है, किन्तु बहुत कम नहीं हो सकती, क्योंकि वैसा होने से 'अपना काम' करनेवाले परिवारों की आय और जीवन-स्तर बहुत निम्न स्तरीय रह जायेगा। यही शक्ति के उपयोग का प्रश्न उठता है। अनेक सूक्ष्म संयंत्रों को, उनकी पूरी क्षमता के साथ चलाने का काम हाथ या पशु-शक्ति से नहीं हो सकता। वहाँ यांत्रिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। इससे सवाल उठता है गाँवों में बिजली की पूर्ति का, जिसके लिए अगर हम केन्द्रित शक्ति स्रोत और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड पर निर्भर करते हैं, तो वह आसान नहीं है। भारत की कुल विद्युत शक्त बहूत ऊँची नहीं है और इसे बढ़ाने का महज एक ही उपाय है कि बड़े पैमाने पर कीमती अणु-शक्ति का उपयोग किया जाय। राज्य की नीति है कि गाँवों का यथा शीघ्र विद्युतीकरण किया जाय, किन्तु जिस गति से गाँवों में बिजली लगायी जा रही है, वह उत्साह-वर्धक नहीं है।

इसका हल है 'सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान' जो प्रत्येक गाँव या गाँवों के समूह में शक्ति के अपने स्रोतों का निर्माण करेगा, जो जीजल, स्नाद गैस, वाष्प, जल, वायु तथा सौर ऊर्जा जैसा कुछ होगा। स्रोत चाहे जो भी हो, जब तक प्रत्येक गाँव तक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड न पहुँच जाय, शक्ति की पूर्ति या सूक्ष्म ऊर्जा सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के साथ-साथ चलनी चाहिये।

सुझाया जाता है कि योजना आयोग को सामाजिक क्षेत्र की मौजूदगी कबूल करनी चाहिये और अपनी ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति को उसकी वर्तमान अवस्था तथा उसके स्थिरीकरण एवं विकास के लिए उसकी आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए अभिप्रेरित करना चाहिये। उसके लिए अनेक दिशाओं में अनुसंधान कार्य करना होगा—और उनमें एक दिशा होगी अपने काम के लिए उपयुक्त मयत्र तथा औजारों का अनुसंधान।

जापान तथा यूरोप के जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रिया आदि देशों में लघु तथा कुटीर उद्योगों के आधार पर उत्पादन होता रहा है और अब भी होता है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितना ही पुराना होगा, उसमें ऐसे प्राणवान छोटे और ग्रामीण उद्योगों को ढूँढना उतना ही आसान होगा, जिन्हें भारत के सामाजिक क्षेत्र के लाभार्थ अपनाया जा सकता है।

जहाँ-कहीं तैयार मशीनें या औजार उपलब्ध नहीं हैं, उनके रूपांकन तथा उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग को निमंत्रित किया जा सकता है। विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देने के लिए संगठन तथा संस्थाएँ मौजूद हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि एक ऐसे केन्द्र की स्थापना की जाय जो हमारी आवश्यकताओं का तरतीब से प्रचार और विश्लेषण कर सके और मौजूद समाधानों को सग्रह कर उन्हें उपयोग में ला सके एवं सहयोग तथा सहायता दे सके।

बम्बई १८ फरवरी १९६४

चीनी का स्रोत : ताड़

प्रकाश चन्द्र वासनिय

‘ब्रिटिश होम ग्रेन सुगर इण्डस्ट्री’ के इतिहास से पता चलता है कि बर्तानिया की सरकार ने चुकन्दर चीनी उद्योग को उसका उत्पादन खर्च ज्यादा होते हुए भी उस देश में कृषि के हित में मदद दी। क्या हमारी सरकार उद्योग और कृषि दोनों के हित में ताड़-चीनी उद्योग के पोषाहनाय सहायता नहीं दे सकती ?

नीरा की राव बनाने में—यहाँ तक कि पेड पर लटकी हँडिया में नीरा टपक रहा हो उस अवस्था में भी—विजली का इस्तेमाल करने के तर्क के पीछे एक उद्देश्य है, ताड़ चीनी का उत्पादन खर्च कम करना। लेकिन कोई भी यह पूछ सकता है कि “देश में जब गन्ना-चीनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तब यह सब इन्क्यूट क्यों मोठ लिया जाय ? गन्ना-चीनी उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत चीनी के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि वह उसका निर्यात करने की स्थिति में भी है। तब हम क्यों इस उद्योग में बाधा खड़ी करें और क्यों हम अपना चीनी-स्रोत बदलें ?”

इंग्लैण्ड में जब ‘बीट सुगर सोसायटी’ ने घरेलू चीनी उद्योग की सहायता के लिए अपना आन्दोलन चलाया तब वहाँ भी कुछ लोगों ने ऐसे ही प्रश्न उठाये थे। वहाँ के लोगों को सस्ती चीनी मिल रही थी और यह बात उपनिवेशवादी उद्योगपतियों के हित में थी कि घरेलू बाजार केवल उनकी परिष्कृत गन्ना चीनी के लिए ही रहे। इसलिए जब सहायता की माँग की गयी तो बर्तानिया सरकार ने प्रथम दस वर्ष के लिए ही सहायता स्वीकृत की और तब मामले का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की।

इंग्लैण्ड का घरेलू चीनी उद्योग

उक्त समिति का प्रतिवेदन और वहाँ की सरकार के निर्णय से हमें शिक्षा मिलनी चाहिये। इसलिए इंग्लैण्ड के घरेलू चीनी उद्योग (ब्रिटिश होम ग्रेन सुगर इण्डस्ट्री)

का संक्षिप्त ऐतिहासिक चित्र, यहाँ प्रस्तुत करना अप्रासंगिक नहीं होगा।

चुकन्दर में निस्सारित चीनी के रवे (क्रिस्टल) का पहली बार उत्पादन प्रमा में १७४७ में हुआ, लेकिन उक्त खोज का लाभ उठाने के लिए कारखानों की स्थापना उसके ५० वर्ष बाद हुई। इस विचार ने विस्तृत क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। नेपोलियन-कालीन युद्धों में फ्रान्स ने इसका अच्छा फायदा उठाया। नेपोलियन ने चुकन्दर की खेती और उसके निस्सारण तरीके की खोज-बीन की तथा उसके बाद फ्रान्स में चुकन्दर से चीनी का उत्पादन करने को प्रोत्साहन देने के लिए ‘आर्थिक सहायता’ की पद्धति का सृजन किया। राज्य सहायता न केवल चुकन्दर उत्पादक किसानों को, बल्कि कुशल उत्पादन तरीके के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु वैज्ञानिकों व अन्य व्यक्तियों को भी दी गयी। परिणाम-स्वरूप फ्रान्स में सैकड़ों चीनी उत्पादन कारखानों की स्थापना हो गयी और शीघ्र ही वह यूरोप का एक अग्रणी चीनी उत्पादक देश बन गया। यूरोप के प्रायः सभी देशों ने उसका अनुसरण किया और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक यह उद्योग समुक्त राज्य अमेरिका तक फैल गया जहाँ पहले की खेती, दक्षिण में, पहले से ही सुस्थापित हो चुकी थी।

यूरोप में हुए अनुभवों से दो महत्वपूर्ण बातें स्थापित हुईं (१) कि चुकन्दर से चीनी बनाना प्राविधिक दृष्टि से एक शक्य बात है, और (२) चुकन्दर की खेती

का सामान्यतः खेती पर और खाम कर पशुधन की तादाद बनाये रखने हेतु बहुत ही लाभदायक प्रभाव पड़ता है।

नेपोलियन के जमाने में ही उक्त बात भलिभौति स्थापित हो चुकी थी, फिर भी बर्तानिया की सरकार की तन्मबधी प्रतिक्रिया जानना रुचिकर होगा।

चीनी उद्योग सम्बन्धी जाँच

ग्रेट ब्रिटेन में चीनी उद्योग स्थापित करने के लिए १८३२ में ही व्यक्तिगत प्रयास होते रहे हैं, लेकिन उच्च उत्पादन लागत के कारण ये सब प्रयास निरर्थक रहे। फ्रान्स तथा अन्य देशों की सफलता ने ब्रिटेन के किसानों और उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए आर्थिक सहायता के लिए १९२५ में सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और वहाँ की पार्ल-मेण्ट ने दस वर्ष के लिए आर्थिक सहायता—यद्यपि कम पैमाने पर—स्वीकार की। उक्त दस वर्षीय उप-दानावधि में विश्व बाजार में चीनी के भाव काफी गिर गये। इसलिए बर्तानिया की सरकार ने १९३४ में एक समिति नियुक्त की कि वह चीनी के 'यूनाइटेड किंगडम' में उत्पादन, परिष्करण और वितरण को शामिल करते हुए तथा घरेलू चुकन्दर-चीनी उद्योग और आयातित चीनी सहित चीनी उद्योग की अवस्थाओं की जाँच करे तथा ऐसा करते वक्त वह 'एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एक्ट' के अन्तर्गत इस उद्योग के ढाँचे में होनेवाले परिवर्तनों को ध्यान में रखे, उसके आचरण के सम्बन्ध में और खास कर आवश्यक समझी जानेवाली राज्य सहायता के बारे में सिफारिश करे।"

उक्त समिति ने सिफारिश की "चूँकि हमारे सामने प्रस्तुत सभी तथ्यों का मूल्यांकन करने पर एक ऐसे उद्योग पर जिसकी कभी भी आत्मनिर्भर बनने की उपयुक्त सम्भावना दिखायी नहीं पड़ती, तथा एक ऐसी फसल पर जोकि सहायता के बिना वर्तमान चीनी मूल्यों के अनुसार प्रायः मूल्यविहीन होगी, हमें हर वर्ष लाखों की रकम के खर्च के लिए कोई सोद्देश्य औचित्य दिखायी नहीं पड़ता, इसलिए हम सहायता

जारी रखने की सिफारिश नहीं कर सकते।"

इसके बावजूद सरकार ने प्रतिवेदन के इन शब्दों को अधिक महत्व दिया "अन्त में हम इस उद्योग को राज्य सहायता देना जारी रखने के लिए जो सब से अधिक महत्वपूर्ण दलील—कृषि के लिए एक राहत प्रदान करने वाले उपाय के रूप में इसका मूल्य—लगती है, उस पर आते हैं। अनेक गवाहों ने हमें बताया कि चुकन्दर चीनी को राज्य सहायता से कृषि को बहुत बड़ा सहारा मिला—चुकन्दर उपजानेवाले क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तथा सारे देश में परोक्ष रूप से—और वह भी खास कर ऐसे समय में जबकि मास तथा डेरी उत्पादनों के भाव बुरी तरह गिर जाने की वजह से उत्पन्न मंदी की स्थिति हो, अनेक क्षेत्रों में पशुओं की चरगई के लिए परम्परागत कदमूलों की पैदावार लाभदायक नहीं रही हो और उनकी महज क्रमानुसार खेती में नुकसान ही होता हो, तथा खाद्यान्नों के भाव गिर जाने की स्थिति में जिसे शायद ही वर्दाश्त किया जा सके। चुकन्दर की खेती ने अन्य अलाभ-दायक फसलों का एक लाभदायक फसल के रूप में स्थान ले लिया है और खाद्यान्न फसलों का सहारा बन गयी है। हमें बताया गया कि इसके बिना पूर्वी जिलों (काउण्टीज) में काफी जमीन कृष्य भूमि नहीं रह पाती। ऐसी कुछ भूमि में—और अन्य क्षेत्रों की भूमि में भी—चरागाह हो जाते, पर इसमें अधिकांश भूमि इस उपयोग के योग्य नहीं है और उसे पूर्णतः त्याग दिया जाता।

"हमें सन्तोष है कि चुकन्दर उद्योग में कृषि को काफी सहायता मिली है और जहाँ चुकन्दर की खेती होती है, वहाँ उसने प्रत्यक्ष राहत पहुँचायी है।... तथापि, पिछले वर्षों में कृष्य भूमि को चरागाहों में परिवर्तित करने की तथा कृषि और चरागाहों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र को कम करने की सामान्य प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए यह मानना उचित होगा कि चुकन्दर को विशेष महत्व प्रदान करने के पल्लवस्त्र कुछ सीमान्त कृष्य भूमि खेती के अन्तर्गत रखी गयी है अथवा बर्बाद होने से बचायी गयी है।"

वर्तमानिया की सरकार ने अपनी भावी नीति निर्धारित करने में विशेष समय नहीं लिया। केवल चार महीने बाद जुलाई १९३५ में एक 'इवेत पत्र' के रूप में उसकी घोषणा की गयी। इवेत पत्र में कहा गया "सरकार इस निर्णय पर पहुँची है कि कृषि-विषयक आधारों पर यह वाञ्छनीय है कि सहायता दे सकने की बिना किसी विशिष्ट मीमांसा के निर्धारण के चुकन्दर-चीनी उद्योग को सहायता देना जारी रखा जाय।"

इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसे उद्योग को सहायता देने का निर्णय किया जो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल लाभप्रद नहीं था और न ही उसके कभी वैसा होने की कोई आशा थी। इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश मुगर कॉन्फ़ेक्शन ने १९६१ में इसकी जुबली मनायी। उस वक्त उमने 'होम ग्रोन मुगर' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका प्रारम्भ इन शब्दों के साथ होना है 'ब्रिटेन में जितनी चीनी का उपभोग होता है उसका करीब एक-चौथाई हिस्सा परिपूर्ण रूप से इन द्विपों में तैयार किया जाता है।' जिस उद्योग को केवल कृषि के हित की दृष्टि से सहायता दी गयी थी वह अब ग्रेट ब्रिटेन की आवश्यकता की एक-चौथाई चीनी तैयार कर रहा है। प्रारम्भिक अवस्था में चुकन्दर की जड़ की क्या स्थिति

विकसित कर लिया गया है कि चुकन्दर का वजन अब औसतन डेढ़ पौण्ड है तथा उसमें शर्करा-सत्व २० प्रतिशत और किन्हीं मामलों में तो उसमें भी अधिक है।'

इस प्रकार विकास का चित्र कुछ ऐसा है एक ऐसा उद्योग जो उद्योग के रूप में लाभदायक नहीं था लेकिन उसे कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता दी गयी और ऐसे ठोस आधार पर विकसित किया गया कि आज वह एक आर्थिक दृष्टि से लाभदायक उद्योग बन गया है। क्या कोई ऐसे ही आधार है कि उनके अनुसार ताड़-चीनी उद्योग के विकास का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है ?

भारत में ताड़ वृक्ष

ताड़ की नौ किस्में ऐसी हैं, जिनमें मीठा रस प्राप्ति होता है। इनमें से चार किस्में भारत में पायी जाती हैं। उनके नाम हैं ताड़ खजूर, माढी अथवा पनई नाड, नारियल और सागू। उनकी प्रति एकड़ रस-प्राप्ति, नीरा में मुक्तोज प्रातिगत्य और चीनी प्रदान करने की क्षमता सम्बन्धी विवरण तालिका १ में दिया गया है।

इन चार किस्मों में से हम प्रस्तुत लेख में नारियल के पेड़ पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उसके रस की अपेक्षा

तालिका १

ताड़ वृक्ष	प्रति पेड़ प्रति मौसम औसत नीरा प्राप्ति (पौण्ड में)	प्रति एकड़ वृक्षों की संख्या	प्रति मौसम प्रति एकड़ नीरा प्राप्ति (पौण्ड में)	नीरा में औसतन मुक्तोज प्रातिगत्य	प्रति एकड़ चीनी की सम्प्राप्ति	
					ग्रामोद्योगी तरिके से ७ % लॉग टन	वैक्यूमेटिक ९ % लॉग टन
खजूर	३२०	६४०	२,०४,८००	१२	६२४	८
माढी	७८०	६८०	२,९९,२००	११७	१३२१	१९५६
सागू	२,५००	१००	२,५०,०००	९७	७६२	—
नारियल	८००	८०	३२,०००	१५८	—	—

थी ? उन्हीं के शब्दों में "इस पादप—जिसे जगली चुकन्दर कहा जाता है—की जड़ केवल कुछ औंस की थी और उसमें शर्करा-सत्व मात्र पाँच प्रतिशत के करीब था, लेकिन उस स्थिति में आज उसका इस हद तक

कृषकों के लिए उसका फल अधिक लाभप्रद है। तथापि, १८९८ विम्बुन अन्वेषण का विषय है। शेष तीन किस्मों में भी किसी एक का किसी विशेष क्षेत्र को लेकर अन्वेषण के लिए विषय के रूप में चुनाव किया जा सकता है।

तालिका १ में सर्वाधिक आकर्षक बात है ताड़ वृक्षों की अपनी प्राकृतिक अवस्था में चीनी प्रदान करने की क्षमता। ये आकड़े अपनी प्राकृतिक अवस्था में उगे ताड़ वृक्षों से प्राप्त वास्तविक 'प्राप्ति' के अध्ययन में इकट्ठे किये गये हैं। अब तक न तो इन पेड़ों की नम्ल चुगार की दिशा में ही कोई प्रयास किया गया है और न ही उन्हें पानी तथा खाद देने की तरफ कोई विशेष प्रयत्न किया गया है। फिर भी, अपनी प्राकृतिक दशा में ताड़ वृक्ष चीनी प्रदान करने के स्रोत के रूप में आज की उन्नत गन्ने की किस्म अथवा चुकन्दर से श्रेष्ठ है। ऊपर तालिका २ में बुनिन्दा देशों के गन्ने की किस्मों, ग्रेट ब्रिटेन के चुकन्दर और ताड़ वृक्षों में प्राप्त चीनी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इस तुलना में प्रकट होता है कि चीनी प्रदायक

योगिता करने में समर्थ हो सकती है।

अन्वेषणार्थ क्षेत्र

अन्वेषण करने और नस्ल सुधारने के लिए ये एक विस्तृत व व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। कोयम्बतूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्था (कैन ब्रिडींग इन्स्टीट्यूट) का अनुभव हमारे सामने है, जो १९१२ में शुरू की गयी थी और दस वर्ष की अवधि में ही उसने गन्ने की किस्में सुधारने की दिशा में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है। ताड़ प्रजनन संस्था राष्ट्र के लिए और भी अधिक लाभदायक साबित हो सकती है तथा वह ऐसे ताड़ की किस्मों का विकास कर सकती है जो ज्यादा नीरा प्रदान करे एवम् जिनमें ज्यादा शर्करा-सत्व हों। पेड़ की ऊँचाई, प्रौढ़ावस्था प्राप्त करने की अवधि, मौसम-काल आदि

तालिका २

देश	स्रोत	वर्ष	प्रति एकड़ चीनी सम्प्राप्ति (लॉन्ग टन में)
ब्रिटेन	चुकन्दर	१९५९-६०	१३४०
पेरू	गन्ना	" "	५.०७६
आस्ट्रेलिया	"	" "	४०६०
मोरीसियस	"	" "	३०८८
फिलीपाइन्स	"	" "	२७९३
क्यूबा	"	" "	२०९५
भारत	"	" "	१४४८
	माढी	—	१५२१ से १९५६
	खजूर	—	६२८ से ८००
	सागू	—	७६२

कारक के रूप में ताड़ वृक्ष गन्ने से कितने ही श्रेष्ठ है। माढी अर्थात् पनई ताड़ अपनी वर्तमानावस्था में भी सभी किस्मों में श्रेष्ठ है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि खजूर की चीनी प्रदायक क्षमता इस हद तक सुधारी जा सकती है कि वह चुकन्दर चीनी की प्रति-

जैसी अन्य समस्याओं का भी उक्त संस्था कर सकती है। तालिका २ में प्रस्तुत आँकड़ों पर सामान्य दृष्टि डालने पर भी कोई यह प्रश्न पूछने के लिए उद्यत हो सकता है कि अब तक ताड़ वृक्षों का उनमें सम्भाव्यताएँ होते हुए भी परिपूर्ण उपयोग क्यों नहीं किया गया? इसका

कारण ढूँढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। प्रथम, इसकी सम्भाव्यता सदैव ही प्रति एकड़ के स्थान पर प्रति पेड़ के हिसाब से आँकी गयी है और इसलिए इसकी गन्ने से तुलना नहीं की गयी। द्वितीय, इसके रस अर्थात् प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव से नीरा में १० प्रति शत गुड़ प्रदान करने की क्षमता सिद्ध हो चुकी है। चीनी के लिए यह तत्व न्यूनतम सात प्रति शत और अधिकतम

कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत तथा अब खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत ताड़-गुड़ विभाग ताड़-गुड़ उद्योग का विकास करने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए तत्सम्बन्धी आकड़ विश्वस्त समझे जा सकते हैं। इन

इन आँकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ६० लाख टन गुड़ और ३० लाख टन चीनी तैयार करने के लिए आवश्यक ताड़ वृक्षों के लिए क्रमशः

तालिका ३

पेड़	प्रति एकड़ नीरा (पौड़ में)	१० प्रति शत के हिसाब से प्रति एकड़ गुड़ प्राप्ति (लॉग टन में)	आठ प्रति शत के हिसाब से प्रति एकड़ चीनी की प्राप्ति (लॉग टन में)	पेड़ के छेदन की अवधि (वर्षों में)
खजूर	२,०४,८००	८ ९३	७ १३	२५ से ९०
माढी	२,९९ २००	२१ ७४	१७ ३९	७० से ९५

नौ प्रति शत है तथा हम अपने देश के ताड़ वृक्षों के लिए यह प्रातिगन्य औसतन आठ ले सकते हैं। प्रति एकड़ औसत नीरा प्राप्ति और उससे चीनी सम्प्राप्ति के प्रातिगन्य हेतु मैं केवल खजूर तथा माढी ताड़ पर ही विचार कर रहा हूँ। ये पेड़ प्रायः सभी राज्यों में पाये जाते हैं और उनका छेदन होता है। दक्षिण भारत में माढी ताड़ को और उत्तर भारत में खजूर ताड़ को तरजीह दी जाती है। नीरा में खमीर को रोकने के लिए केवल रासायनिक तरीके से ही कोशिश की गयी है। अभी तक किसी यांत्रिक तरीके का विचार नहीं किया गया है। तृतीय, इस शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में कुछ कारखानों ने पुराने तरीके से गुड़ से चीनी बनाने का प्रयत्न किया। उनके अवैज्ञानिक तौर-तरीके के कारण बहुत-कुछ मुक्तोन्नत तत्व बेकार चला जाता और फलस्वरूप इस वर्षादी के लिए कहाँ यह गया कि शर्करा-तत्व की कमी है। उस असफलता का भूत आज भी अनेकों के दिमाग में छाया हुआ है।

ताड़-गुड़

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद पहले केन्द्रीय खाद्य और

चार लाख एकड़ तथा ढाई लाख एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार कुल भूमि की आवश्यकता ६ लाख ५० हजार एकड़ होगी।

गन्ना बनाम ताड़

जब यह उद्योग भारत के लिए आवश्यक गुड़ और चीनी की मात्रा ६ लाख ५० हजार एकड़ भूमि से पूरी कर सकता है तब हमें गन्ने में ही चीनी क्यों बनानी चाहिये, जिसके लिए ५० लाख एकड़ जमीन की जरूरत होती है। हम यह अच्छी तरह सोच सकते हैं कि लगभग ५० लाख एकड़ अच्छी भूमि की बचत में देश को परीक्षण रूप से कितना लाभ होगा। यह सही है कि गन्ने की फसल वार्षिक रूप से होती है और वार्षिक फल-प्राप्ति के कारण ऐसा करना विनियोजक के लिए लाभकारी है। इसके विपरीत ताड़ वृक्षों से फल प्राप्त होने में कुछ समय लगता है। तथापि, सरकार यह कठिनाई दूर कर सकती है। कुछ अन्य वृक्षारोपण उद्योग हैं, जिन्हें प्रारम्भिक अवस्था में सरकार सहायता देती है। इसलिए यह तय करना सरकार का काम है कि ताड़ वृक्ष उगानेवाले कृषकों को वह कितने समय तक कितनी सहायता देगी।

खजूर का पेड़ छह में आठ वर्ष का होने पर और माढ़ी १२ में १५ वर्ष का होने पर नीरा देना शुरू करता है। लेकिन एक बार शुरू होने पर खजूर का पेड़ २५ में ९० वर्ष तक और माढ़ी का पेड़ ७० में ९५ वर्ष तक नीरा देता रहेगा। और फिर, गन्ने की खेती में बोआई के लिए प्रति एकड़ ६०-७० मन गेण्डी की आवश्यकता भी तो पड़ती है।

इसका अर्थ है गन्ना बोने के लिए प्रति वर्ष कम से कम प्रति एकड़ १०० रुपये की गेण्डी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार ५० लाख एकड़ में गन्ने की बोआई करने के लिए ५० करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। यदि हम ताड़ वृक्ष की उम्र ७० वर्ष मानें तो ताड़ वृक्षों की जगह गन्ने की बोआई करने के लिए उक्त अवधि में ४१ अरब ३० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

एक बार ताड़ वृक्षारोपण के लिए स्थल का चुनाव करने पर उस स्थान का सदैव के लिए ताड़ वृक्ष उगाने के लिए इन्तेमाल किया जा सकता है। ये पेड़ २० से ४० फुट तक और किन्हीं मामलों में तो और भी अधिक ऊँचाई तक बिना किसी शाखा के बढ़ते हैं। इसलिए वे पुराने पड़ जायें उससे पहले ही ताड़ प्रजनन संस्था में विकसित अच्छी किस्म के ताड़ इन पेड़ों के बीच-बीच में लगाये जा सकते हैं। नये पेड़ तैयार होने पर पुराने वृक्षों को काट कर हटाया जा सकता है। इस प्रकार एक बार ताड़ बाग खड़ा हो जाने पर वह सदैव ही ताड़ बाग बना रह सकता है तथा मौसम-काल में नित्य नीरा प्रदान करता रहेगा। इसलिए जब हम चीनी का स्रोत गन्ने से बदल कर ताड़ को बनाने की सोचें तब प्रारम्भिक काल में ताड़ वृक्ष लगानेवाले को सहायता का दिया जाना आवश्यक है।

यह मुस्थापित हो चुका है कि इस परिवर्तन से भारत कोई ५० लाख एकड़ से भी अधिक भूमि बचा सकेगा। इस प्रकार की भूमि सर्वोत्तम किस्म की होगी, जिसे पानी और खाद दी जा सकती है। बड़ी आसानी से यह माना जा सकता है कि इस भूमि में किसान दो खाद्यान्न फसले पैदा करेगा अथवा साक-भाजी की खेती करेगा या फिर उसमें फलोद्यान लगायेगा। इन कामों से गाँवों के भूमिहीन श्रमिकों को गन्ने की खेती से अधिक रोजगारी मिलेगी। इस प्रकार गन्ने के स्थान पर ताड़-

चीनी के प्रतिस्थापन में किसी प्रकार की बेरोजगारी पैदा नहीं होगी। इसके विपरीत ३०० लाख वृक्षों के पीछे एक छेदक के हिसाब में समग्र ताड़ वृक्षों से १३,८०,००० छेदकों को रोजगारी मिलेगी। इसके अलावा छेदकों की सहायता करनेवालों, उनके उपकरण बनानेवालों आदि के रूप में अन्यान्य लोगों को भी रोजगारी मिलेगी। कुछ अन्य वृक्षारोपण सम्बन्धी उद्योग भी हैं, जो गाँवों में बेरोजगारी की समस्याएँ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताड़ के बागानों से कितने लोगों को काम मिल सकता है, इसका अनुमान निम्न तुलनात्मक आँकड़ों से लगाया जा सकता है चाय (१९५४) ९,९३,५९४, काफी (१९५५-५६) २,२७,०३३, रबड़ (१९५६) ६३,०३४, गन्ना चीनी (१९५६) १,०४,००० तथा कर्मचारी गण १९,३००। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि रोजगारी देने की दृष्टि में ताड़ बागान सत्र में बड़ा उद्योग होगा।

बहुत अच्छी ५० लाख एकड़ में ज्यादा जमीन की उपलब्धि से फिलहाल हम खाद्यान्नों के आयात पर हमारी जो विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं, और ज़िम्मेदारी कम है, उसमें बचत की जा सकेगी।

अपने जयन्ती प्रकाशन में 'ब्रिटिश सुगर कारपोरेशन' ने बताया है कि द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजों ने महसूस किया कि घरेलू चीनी उद्योग ने न केवल उनकी विदेशी मुद्रा ही बचायी, बल्कि अन्य अनेक समस्याएँ हल करने में मदद भी दी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इसी प्रकार के लाभ ताड़-चीनी उद्योग से भी प्राप्त हो सकते हैं।

यदि हम इसकी रोजगारी देने सम्बन्धी क्षमता, भूमि बचत की शक्ति और विदेशी मुद्रा में बचत करने की क्षमता महसूस करें तो ताड़ चीनी उद्योग के विकासार्थ क्या किसी अन्य औचित्य की आवश्यकता है? यदि ब्रिटेन की सरकार मात्र कृषि के हित में चुकन्दर चीनी उद्योग को सहायता दे सकती है तो कोई कारण नहीं कि भारत सरकार कृषि तथा रोजगारी, दोनों के हितों की दृष्टि में ताड़-चीनी उद्योग को सहायता क्यों नहीं दे सकती।

इन्दौर २६ मार्च १९६४।

पंचायत राज

पुरुषोत्तम प्रभाकर

गाँवों में सामाजिक विकास के उद्देश्य से चलनेवाली कार्यशीलताओं का मुख्य आधार होंगी तीन मस्थाएँ—पंचायत, मजदूरी समिति और विद्यालय। गाँवों में विभिन्न दस्तकारियों और प्रामोद्योगों से सम्बद्ध उत्पादन-मह-प्रशिक्षण केन्द्रों का एक जाल-सा बिछा दिया जाना चाहिये। इस प्रकार के केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को मजदूरी समितियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

संसदीय जनतंत्र का मूल तत्व है जनता का विश्वास प्राप्त नेतृत्व पैदा करना और उनकी आकांक्षाओं को व्यावहारिक रूप देकर उन्हें बरकरार बनाये रखना। कहीं ऐसा न हो कि अधिकांश नये आजाद देशों की तरह भारतीय जनता की आकांक्षाएँ भी राष्ट्रीय स्रोतों और परिस्थितियों के अनुरूप न हों, इसलिए आवश्यक है कि तात्कालिक महत्व के कार्यों में प्रत्यक्ष भाग लेने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया जाय, ताकि उसमें मापेक्ष और जिम्मेवारी की भावनाएँ भरी जा सकें। आखिरी व्याख्या में, कहा जाता है, राष्ट्र के सामाजिक पुनर्निर्माण में लोगों के समुदाय के रूप में स्वयंस्फूर्त ऐच्छिक सहयोग को सुनिश्चित करके ये बातें उनके विकास की गति के धीमेपन को तीव्रता प्रदान करती हैं।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी नये आजाद कल्याणकारी राज्यों में हो रहे सामाजिक पुनर्निर्माण कार्य की व्यापकता और विशालता सरकारी यंत्र के लिए बहुत जल्दी बना देती है कि वह इस कार्य के साथ जनता को लेकर चले और उसी के अनुरूप कार्यों का विकेंद्रीकरण भी करे। इसमें बढ़ कर, छोटे समुदायों के सौर्य और सहकारिता की शक्ति के जरिये जनतांत्रिक मस्थाओं की आदर्श नींव डाली जा सकती है। दरअसल, तभी मानव समाज छोटे समुदायों के बीच गहरे सबंध स्थापित करने की अपनी महान्तम प्राप्ति प्राप्त कर सकता है और महज उसी की बदौलत सामूहिक प्रयामों को बढ़ावा मिल सकता है।

अब प्रश्न उठता है कि 'भागीदारी' के सम्बोध का तात्पर्य क्या है और उसका आशय क्या है? जनता की सामुदायिक भागीदारी के सम्बोध के दो पहलू हैं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसका तात्पर्य है स्वयं और मृजनात्मक जनमत तैयार करना जबकि स्थानीय स्तर पर इसका मतलब है समुदाय के स्रोतों की वास्तविक भागीदारी और उनका संरक्षण। ऐसे ताने-बाने में सरकारी यंत्र से यह उम्मीद की जाती है कि वह योजनाबद्ध विकास के लिए तकनीकी सहायता, ऋण की सुविधाएँ तथा विशेषज्ञों की सलाह की व्यवस्था के जरिये उच्च स्तर पर लोकप्रिय मस्थाओं के क्षेत्र और प्रभाव के विस्तार में योगदान करेगी।

ऐसी भागीदारी के लिए दार्शनिक ढाँचा, हमारे सविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों—जो व्यष्टि को समष्टि के अन्तर्गत मानते हैं—न कि उसके बाहर—में निहित दर्शन प्रदान करता है। समाज के ढाँचे में ही व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का महत्व है और उसमें ही उनका उपयोग किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर, यह दर्शन हमारे सविधान में राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों में से एक में स्पष्टतः इस प्रकार से व्यक्त है “राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन और उनको ऐसे अधिकार तथा शक्ति से सम्पन्न करने के लिए कदम उठायेगा जो उनको स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बनाने के लिए जरूरी होगा।”

अनादिकाल से भारत में स्वशासित ग्रामीण सस्थाओं की जड़े जमी हुई हैं। 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया' (भारत की खोज) नामक पुस्तक में एक स्थान पर शकटाचार्य के नीतिमार्ग में वर्णित आज में १० गनाब्दी पहले में भारतीय गाँवों तथा ग्राम परिपदों और उन प्रारम्भिक दिनों में बहुत हद तक प्रचलित ग्रामीण स्वराज्य का जिक्र आता है। आज के युग में कुछ पहले मन् १८३० में सर चार्ल्स मेटकाल्फ (Sir Charles Metcalfe) ने लिखा था—“छोटे गणतंत्र, जिनके पास अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ मौजूद थीं और जो बाह्य सम्बन्धों में मुक्त थे ... प्रत्येक क्षेत्र में एक छोटा राज्य था।” यहाँ तक कि स्वशासन के धुंधले स्वरूप की कल्पना के समय भी मण्टेग्यू चेम्सफोर्ड (Mantagu Chelmsford) प्रतिवेदन के लेखक ने कहा था—“जिस दिन स्वशासन प्राप्त हो जायगा, रय्यत की बुद्धि जागृत करनेवाली, उसको स्वतंत्र एवं स्वयं निर्णय करनेवाला मानव बनाने में मदद करनेवाली हर चीज तेज गति में उसके पास आ जायेगी।” हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के लम्बे वैचित्र्यपूर्ण इतिहास में हम लोग कभी भी अपनी ग्रामीण इकाइयों के उद्देश्य को नहीं भूले और उन इकाइयों ने वर्तमान गन्दर्भ में स्वदेशी आन्दोलन में सक्रिय भूमिका अदा करके इस कार्य के लिए अपनी योग्यता (क्षमता) का अनुकूल सिद्ध किया है।

पंचायत, सहकारिता और पाठशाला

किन्तु गुजरे जमाने में इन सस्थाओं के मुनहले चित्र जसी कोई बात नहीं थी। ये बहुत हद तक गुटबाजी और जात-पात के विभेद, अत्याचार और गतिहीनता से भरी थी। फिर भी ये सस्थाएँ सामाजिक सामंजस्य का मूल केन्द्रबिन्दु रही और उन्होंने प्राचीन मूल्यों की शाश्वतता को बरकरार रखा। वर्तमान अवस्थाओं के अनुकूल ग्रामों का पुनर्निर्माण करने के बाद ही ग्रामीण जनतंत्र में आधुनिक जनतांत्रिक सरकारों की मुदृढ़ नींव डाली जा सकती है। हमें ग्रामीण जीवन का निर्माण इस प्रकार करना चाहिये जिससे कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों को

सुरक्षित रखते हुए आधुनिक तकनीकी तथा वैज्ञानिक सभ्यता की अपेक्षाएँ अच्छी तरह पूरी कर सके। वैज्ञानिक तकनीक इस्तेमाल करने में अधिक महत्वपूर्ण है “बेहतर जीवन के लिए चाह” पैदा करने और निम्न गुटबाजी की भावना में ऊपर उठने तथा जन-समुदाय तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के रूप में सोचने के लिए लोगों का मनोवैज्ञानिक अभिस्थापन करना। स्वावलम्बन और सहकार के आधार पर सावधानीपूर्वक बनाये गये अनेक सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों द्वारा दृष्टिकोण में यह परिवर्तन लाने की आशा की जाती है। इस आंदोलन का सार यह है कि हर परिवार इसके प्रभाव में आये। अपने सार्वजनिक दृष्टिकोण में निम्नतम स्तर पर यह (दृष्टिकोण) ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति और ग्रामीण पाठशाला को श्रृंखलाबद्ध करने में व्यक्त होना चाहिये। पंचायत तथा सहकारी समिति, सामाजिक और आर्थिक विकास को अपने लक्ष्य के रूप में गान कर प्रशासनिक और नियमन कार्य करेगी और पाठशाला समस्त समुदाय को संगठित करेगी तथा विशेष कर आनेवाली पीढ़ी में सहकार की भावनाएँ भरेगी।

सरकारी सहायता

ये सस्थाएँ वांछित दिशा में विकसित हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रारम्भिक चरणों में उच्च स्तर पर सामुदायिक विकास अभिकरण उनके लिए सलाह, सेवा और पूर्ति की व्यवस्था करके मदद करे। इस प्रकार इस आन्दोलन ने सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय विस्तार योजना का रूप धारण किया है। यद्यपि बिल्कुल शुरू में सरकारी सहायता से ही उसके लालन-पालन की स्थिति को पूरी तरह नहीं ढाला जा सका, तथापि अधिकाधिक मभव मात्रा में आम लोगों का समर्थन प्राप्त करने पर जोर दिया गया। यदि शुरू में ही इन सस्थाओं को पूरी-पूरी जिम्मेवारी सौंप दी गयी होती तो वैसा करना बहुत ही नुकसानदेह होता, क्योंकि इस समय उनकी नींव, दुर्भाग्यवश, चली आ रही अत्यधिक व्याप्त जातीय अत्याचार, गतिहीनता और गुटबाजी की गलत जमीन

पर पड गयी होती। ऐसी स्थिति में यह जरूरी था कि सरकारी अभिकरण के मार्गदर्शन में प्रत्येक परिवार भाग ले और सामुदायिक कार्य सकीर्ण निष्ठाओं की सीमाओं को लॉघ जाय।

फिर स्थिति आयी ग्राम, खण्ड और जिला स्तर पर एक त्रि-सूत्री प्रणाली के आधार पर स्वशासित विधिविहित सगठन बनाने की। इस महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कदम पर विचार करने के पूर्व इस बात का उल्लेख करना उपयुक्त है कि इन स्वशासित सस्थाओं का निर्माण करने के लिए वाछित ब्यौरेवार प्रारम्भिक कार्य पूरा नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय विस्तार मेवा तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और सहकारी समितियों स्थापित करने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। वास्तव में पंचायत राज की स्वशासित सस्थाओं की शुरुआत करने के पहले सारे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों तथा सहकारी समितियों और प्राथमिकता के तौर पर पाठशालाओं का भी जाल बिछ जाना चाहिये था। अगर पंचायत राज की पूरी-पूरी शुरुआत के पहले ये सभी प्रारम्भिक श्रम-साध्य कार्य पूरे कर लिये गये होते तो नीव कितनी सुदृढ होती।

गाँवों में पंचायत, खड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, सास्थानिक परिवर्तन का अपरिहार्य आधार है। ये सस्थाएँ ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पहलू से सबधित रहेगी और उनके अन्तर्गत कार्यों के व्यापक क्षेत्र का समावेश होगा। सभी खड विकास कार्य उत्तरोत्तर रूप से पंचायत समितियों को सौप दिये जायेंगे और पंचायत समितियों अपने अधिकार-क्षेत्र में सभी विकास-कार्यों के लिए पूरी-पूरी जिम्मेवार होगी। इन सस्थाओं को जिम्मेवारी तथा पर्याप्त स्रोतों सहित, प्रभावशाली कार्य करने के लिए, विधिविहित स्वरूप प्रदान किया गया है।

निःसन्देह त्रि-सूत्री स्थानीय प्रशासनात्मक ढाँचे में स्थानीय पहलू को प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय योजनाओं के लिए लोगों की रुचि कायम रखने में

सहायता की है। पंचायत, सहकारी समिति तथा स्कूल—ये तीन सस्थाएँ ग्राम की गतिविधियों की केन्द्रबिन्दु हो गयी हैं।

पंचायत राज का स्वरूप

पंचायत राज के मौलिक स्वरूप के अनुसार, विशेष कर राजस्थान के सन्दर्भ में, पंचायतों को केवल कार्यपालिका के ही अधिकार नहीं थे, बल्कि उन्हें दीवानी और फौजदारी के छोटे-छोटे मामलों को निपटाने के भी अधिकार थे। बाद में न्यायकार्य को कार्यपालिका कार्य से अलग करने तथा प्रत्येक ५ से ७ पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत की स्थापना करने का उचित निर्णय किया गया, जिसके लिए प्रत्येक पंचायत एक सदस्य का चुनाव करती है। ये पाँच से सात सदस्य तीन-तीन सदस्यों की बेच (न्याय-पीठ) बनायेंगे। इन न्याय पंचायतों को सरकार वरिष्ठ स्थानीय सस्थाओं से विचार-विमर्श करके ही अधिकारच्युत और विघटित कर सकती है। ऐसी सस्थाओं के हिसाब का लेखा-परीक्षण किया जायेगा तथा उसका पूरा निरीक्षण एव उममें सशोधन का अधिकार जिला या सेशन जज को होगा। एक अध्ययन दल के नेता ससद सदस्य श्री रघुवीर सिंह ने अपने अध्ययन-दौरे के अनुभव बताते हुए कहा कि “राजस्थान में पंचायत राज एक प्रयोग नहीं, बल्कि जनतंत्र के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ एक जीवन-पथ है। वहाँ की जनता इसे राज्य तथा स्वयं की सेवा के लिए एक अवसर समझती है।”

यथा सभव अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तथा गुटबाजी को निरुत्साहित करने के लिए लगभग प्रत्येक परिवार को पंचायत तथा प्रत्येक पंचायत को पंचायत समिति स्तर पर सबद्ध करने का प्रयास किया जाना चाहिये। प्रत्यक्ष संचालन में यह कार्य परिवारों द्वारा होना चाहिये, न कि परिवारों के लिए। इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि अधिकृत पद-मोपान का स्थान कहीं छोटे दल या गुट न ले ले।

फल, फल तथा अन्य उत्पादन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार तथा ग्रीन्ड की व्यवस्था समस्याओं में प्रतियोगिता की भावना पैदा करने का स्वस्थ उपाय है। ऐसे पुरस्कारों का विस्तार कुटीरोद्योग क्षेत्र तक भी होना चाहिये।

स्रोत

इन स्वायत्त ग्रामन प्राप्त समस्याओं की सफलता का मादण्ड यह होगा कि किस हद तक वे अपने स्रोतों को बढ़ाने में समर्थ हुई हैं, इससे उनकी अपनी गतिविधियों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा। स्रोतों में वृद्धि तथा सामुदायिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कोई भी प्रयास उसी दशा में सफल होगा, जब जनता में सही तौर पर यह विश्वास पैदा किया जाय कि उनके द्वारा दिया गया पैसा स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च होगा। नकद रूप में उन्हें राज्य अनुदान देने के बजाय धीरे-धीरे स्थानीय कर तथा भू-राजस्व की वसूली का अधिकार सौंप देना चाहिये। उसमें उनके हितों (कार्य) और उत्तुंगदायित्व के क्षेत्र बढेंगे।

इनमें से कुछ समस्याएँ जो दूसरी समस्याओं की तुलना में अधिक प्रगतिशील हैं, जो स्थानीय राजनीतिक झझटों में मुक्त हैं, जिनका नेतृत्व गैर सरकारी है, जिन्हें स्थानीय समुदाय के सम्मान और विश्वास के आधार पर लगभग निर्विरोध तथा स्वयस्फूर्त समर्थन प्राप्त है, वे सफलतापूर्वक ऐसे स्रोतों की वृद्धि तथा रक्षा कर सकती हैं जिन्हें करने में राज्य के समक्ष अटकाव तथा खतरे उपस्थित होते हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पचायत, सहकारी समिति तथा पाठशाला जैसी तीन संस्थाएँ गाँव की सामाजिक गतिविधियों की केन्द्रबिन्दु हैं। पचायत के वांछित क्षेत्र में सहकारी समितियों को अपनी स्वायत्त सत्ता कायम रखनी चाहिये तथा गंभीर व्यापार के सिद्धांतों को अपनाना चाहिये। सहकारी समितियों के प्रबन्ध

के लिए आवश्यक कर्मचारियों तथा तकनीकी ज्ञान, उन्नत औजार और सरजामों का प्रवाह राज्य द्वारा स्थापित अनेक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों पर आधारित होना चाहिये।

पचायत समिति स्तर पर या प्रारम्भिक अवस्था में जिला स्तर पर उन्नत कृषि औजार तथा सरजाम बनाने के लिए और लोहारी, बढईगीरी, कुटीरोद्योग, व्यावसायिक शिल्पो आदि का कार्य करने के लिए एक-एक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र होना चाहिये। इन समितियों के उद्देश्य दोहरे होंगे—उत्पादन तथा प्रशिक्षण। गाँव की जनता को, प्रेरणादायक पर्याप्त सामिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए (प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों पर) काम करने और सीखने हेतु भर्ती करना तथा प्रशिक्षण देना चाहिये। जब ऐसे प्रशिक्षार्थी अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो उन्हें सम्बद्ध व्यवसाय में सहकारी समिति बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिये तथा उन्हें इसके लिए ऋण एवम् पेशगी रकम दी जानी चाहिये, जिसका बड़ा भाग सरजाम एवं औजारों के रूप में हो।

उपसंहार

हम न वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति पर आधारित सामाजिक विकास की कल्पना की है। अतः यह जरूरी है कि जिला परिषद के स्तर पर विज्ञान मन्दिरों की स्थापना की जाय और धीरे-धीरे उनका विस्तार पचायत समिति के स्तर तक किया जाय। इन वैज्ञानिक संस्थाओं को अपने आप को ग्रामीण इजीनियरिंग, कृषि के उन्नत तरीकों, भूमि आरक्षण, वागवानी, मत्स्य-पालन (फिशरी), मुर्गी-पालन, लघु स्तरीय उद्योगों की उत्पादकता तथा गाँव की जरूरतों के मुताबिक औजार और सरजाम बनाने सम्बन्धी समस्याएँ हल करने के काम में लगाना चाहिये।

बैलों की आँतों का निर्यात व्यापार

पोन्नूसामी कुप्पु राव

मैकडो हरिजन परिवार कर्माटगानो से पशुओं की आँतें इकट्ठी करके उनका प्रशोधन करने के कुटीर उद्योग में लगे हैं। भारतीय बैलों की आँतों का काफी निर्यात व्यापार होता है।

क्याईखानो के अनेक उप-उत्पादनो में से बैलो, गायो और भैंस-भैंसों की आँतडियों, पशु आँत उद्योग में लगे हरिजन खरीद लेते हैं। आँत के पाइवों को बिना किसी प्रकार की आँच पहुँचाये उनकी चर्बी, पैंने चाकुओं की सहायता से बड़ी कुशलतापूर्वक हटा ली जाती है। उन्हें स्वच्छ पानी में लगातार धोया जाता है। एक बार जिस पानी से आँतें साफ की जाती हैं, उसे बदल दिया जाता है। आँतों में हवा भर कर उन्हें छाया में सुखाने के बाद उन्हें चिपटी करके उनके गोले बना लिये जाते हैं। अन्दाजन एक गोले में नौ पशुओं की आँतें होती हैं। इन गोलों की लम्बाई २०० गज होती है। इन गोलों की आँतों में शोथ, ग्रथि, क्षतचिन्ह, काली गिट्टी, बलगम, मैला, फफूँद, आकीर्णन, रोगाणु, खमीर, दाग आदि जैसे दोष नहीं होने चाहिये।

प्रशोधन स्थल और सफाई

आँतों का प्रशोधन कार्य कस्बों और गाँवों के बाहरी हिस्सों में होता है, जिसके लिए नगरपालिकाएँ तथा ग्राम पंचायतें सहायता देती हैं। जिन स्थानों पर आँतों का प्रशोधन होता है, उन्हें माफ-मुथरा और स्वच्छ रखा जाता है तथा उनमें प्रशोधन करते समय सफाई सम्बन्धी सभी नियमों का बड़ी कड़ाई के साथ पालन किया जाता है। यह शब्दशः कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में मद्रास, केरल, आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा देश के अन्य कई राज्यों में मैकडो परिवार लगे हैं और इस

प्रकार वे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यदि दक्षिण के चारों राज्यों में—मद्रास, मैसूर, केरल और आंध्र प्रदेश में—प्रशोधित आँतों का सग्रह सम्बन्धी काम चलाया जाय, तो प्रति माह दो-दो सौ गज की लम्बाईवाले ५,००० पैकेट उपलब्ध हो सकते हैं।

निर्यात व्यापार

बैल की आँतों को उनकी लम्बाई के हिसाब से अलग-अलग छाँटा जाता है, जैसे ३५-४०, ४०-४५, ४५-५०, ५०-५५, ५५ तथा उससे अधिक मिलीमीटर की लम्बाई वाली आँतें। ऐसी लम्बाई की बैल-आँतों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है—प्रथम, द्वितीय और तृतीय। दस हजार गज लम्बी पशु-आँतों के ५० पैकेट बनाये जाते हैं, फिर उनकी एक गाठ बना दी जाती है, ताकि विभिन्न स्थानों पर उतारने-चढ़ाने में सुविधा हो। कीटाणुनाशक दवाइयों छिटक कर पशु-आँतों की दीर्घक व चींटियों से रक्षा की जाती है।

भारत में इस उद्योग की स्थापना यूरोपवालों ने की। उद्योग की सर्व प्रथम स्थापना कलकत्ता में हुई थी और तत्पश्चात् उसका विस्तार उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के कुछ स्थानों में हुआ। भारतीय बैलों की आँतें स्पेन, स्विट्जरलैण्ड और जर्मनी को निर्यात की जाती हैं। इसके अलावा १८ दिसम्बर १९६३ को दिल्ली में भारत सरकार और पोलैण्ड सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुए भारत-पोलैण्ड व्यापार और भुगतान सम्बन्धी समझौते के अनुसार पोलैण्ड को भी इनका निर्यात किया जा रहा है। विदेशों में भारतीय पशुओं की आँतों की बहुत माँग है।

वहा इनमे सभी प्रकार की कबाब, चटनियाँ आदि डाल कर तैयार की जाती है। पशुओं की आँते पशुओं के ऐसे उप-उत्पादन हैं जिनका भारत में निर्यात होता है और विदेशी मुद्रा का अर्जन। जहाज के लदान हेतु उनका परिमाण कम से कम ३५-४० गॉंठे होना चाहिये, हा, आयातक के सौदे के मुताबिक उनका परिमाण कम-ज्यादा भी हो सकता है। गॉंठों पर वही विवरण होना चाहिये जो बीजक तथा जहाजगानी सम्बन्धी अन्य कागजातों में हो। इसके अलावा गन्तव्य स्थान पर माल की पहचान के लिए माल पानेवाले के निर्देशानुसार अन्य आवश्यक चिन्ह भी लगाने चाहिये।

पशुओं की आँतों के निर्यात के लिए १९४७ के आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत स्विट्जरलैण्ड सहित सभी अनुमन गन्तव्यों के लिए निर्यात लायसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि, भारत सरकार के प्रमुख आयात-निर्यात नियंत्रक (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) में लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रमाण-पत्र

जहाज पर लदान में पहले पशु-आँतों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है। प्रत्येक परेपण के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नगरपालिकाओं और नगर निगमों के मक्षम अधिकारी तथा पशु-चिकित्सक देते हैं।

पशु-आँतों को जहाज पर लदान से पहले १९२३ के कस्टम सम्बन्धी औपचारिकताओं को सरल बनाने से सम्बद्ध, 'इण्टरनेशनल कन्वेंशन' के अनुच्छेद ११ के अन्तर्गत इस बारे में प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है कि माल किस देश से लादा गया तथा उसमें निर्यातकों व माल प्राप्त करनेवाले का नाम और माल का विवरण भी होना चाहिये। उद्गम सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के लिए चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल और अन्य अधिकार प्राप्त वाणिज्य सच सक्षम संगठन हैं।

जहाज पर लदान से पूर्व 'सुपरिण्टेंडेसी कपनी ऑफ इण्डिया (प्रायवेट) लिमिटेड', नम्बर डी ३०६, डिफेन्स कालोनी, नयी दिल्ली अथवा राज्यों में उसकी शाखाओं

में निरीक्षण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाय कि पशु-आँते अच्छी अवस्था में हैं। यह प्रमाण-पत्र १९६३ के निर्यात (मानक नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक है।

पशु-आँतों की गांठें जब निर्यात के लिए तैयार हो तब माल प्राप्त करनेवाले की सूचना के अनुसार निर्यातक को माल का बीमा करवाना पड़ता है। निर्यात जोखिम बीमा करवाना भी वाछनीय है। पशु-आँतों की गांठों का बीजक मद्रास, कोचीन, बम्बई अथवा कलकत्ता में जहाज तक निशुल्क (एफ ओ बी) बनाया जाता है। आँते प्रायः अन्तिम, सम्पुष्ट और अटल उधार-पत्र के अनुसार भेजी जाती हैं। यह उधार-पत्र दर्शनी हुण्डी के समान होता है, जिसकी अशायगी दिखाने पर करनी होती है।

भारतीय पशु-आँतों के लिए स्पेन प्रमुख विदेशी बाजार है। यदि परेपण यानी माल 'अमेरिकन एक्सपोर्ट एण्ड रीस्ट्रिक्टेड लाउन्स' में कोचीन में भेजा जाता है तो वह बर्मोलेना अथवा वेलेंसिया या स्पेन के अन्य किसी भी बन्दरगाह पर ८ से १२ दिन तक में पहुँच जायेगा। अगर वह मद्रास से भेजा जाय तो स्पेन के बन्दरगाहों तक पहुँचने में उसे ३० से ४५ दिन तक का समय लग जायेगा, क्योंकि कभी-कभी माल को विभिन्न बन्दरगाहों पर उतारा-चढ़ाया जाता है।

भारतीय पशु-आँतों को 'आगमाक' के अनुसार श्रेणीबद्ध कर प्रमाण-पत्र देने का सवाल भारत सरकार के विनियम-व्यवस्था और निरीक्षण निर्देशालय (कृषि विभाग) में विचारणीय है।

लम्बाई के अनुसार आँतों को अलग-अलग छाँट लेने के बाद जो बेकार आँत बच रहती हैं उन्हें रासायनिक ढग से पीस कर कार्बनिक खाद बनायी जा सकती है। नयी दिल्ली स्थित भारतीय कृषिक अनुसंधान संस्था ने परीक्षण करने के बाद यह प्रमाणित कर दिया है कि रासायनिक ढग से पेष्टित बेकार आँतों में दम प्रति शत नाइट्रेट होता है।

मद्रास ४ फरवरी १९६४

मुर्शिदाबाद का हाथी दांत शिल्प कमल बनर्जी



पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के हाथी दात उद्योग का दो शताब्दी पुराना इतिहास काफी दिलचस्प है। किन्तु वर्तमान में इस उद्योग के समक्ष समुचित मूल्य पर हाथी दात की पर्याप्त पूर्ति तथा तैयार वस्तुओं के विक्रय की समस्या है।

मुर्शिदाबाद जिले का हाथी दात शिल्प समूचे भारत में और विदेशों में भी उतना ही मशहूर है, जितना जिले का रेशम उद्योग। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य (१८५१ में) लंदन की प्रदर्शनी में रखी गयी मुर्शिदाबाद की बनी हाथी दात की वस्तुओं की सराहना करते हुए प्रोफेसर रायले (Royle) ने १८५२ में प्रकाशित अपनी पुस्तक में लिखा था

“भारत के विभिन्न हिस्सों से हाथी-दात-शिल्प के नमूने भेजे गये हैं, जो आकार की सूक्ष्मता, विवरण की सुसम्पन्नता या रूप-चित्रण की यथार्थता की दृष्टि से बड़े ही मुग्धकारी हैं। इन सब में बरहमपुर का शिल्प विशेष उत्कृष्ट है वहाँ चित्रित हाथी एवम् अन्य पशुओं के स्वरूप इतने स्वाभाविक हैं कि उन्हें वास्तविक कलाकारों की ही कृति समझनी चाहिये और उन्हें महज हस्त-कौशल की श्रेणी में रखने की बजाय उत्कृष्ट कला की श्रेणी में रखना चाहिये।”

दो शताब्दी पुराना शिल्प

सन् १८८८ में लंदन की प्रदर्शनी में फिर से मुर्शिदाबादी हाथी-दात-शिल्प को भारत में सर्व श्रेष्ठ होने की सनद मिली। ‘समस्त सच्ची भारतीय कला की परिपूर्णता, सूक्ष्मता तथा विदग्धता’ के लिए उनकी प्रशंसा की गयी।

आज दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, मुर्शिदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम में हाथी-दात का शिल्प चल रहा है। मुर्शिदाबादी

शिल्प में विशेषता यह है कि एक खास वर्ग के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से इसी काम को करते आ रहे हैं और वे मुख्यतः मुर्शिदाबाद जिले के बरहमपुर और जिआगज नामक स्थानों में ही रहते हैं। लगभग दो शताब्दी पहले बंगाल के नवाबों के जमाने में १८ वीं सदी में मुर्शिदाबाद तीन पूर्वी सूबों की राजधानी थी। हाथी-दांत का शिल्प वहाँ उसी जमाने से शुरू हुआ। उससे पहले का कोई ऐसा प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिलता कि बंगाल में यह शिल्प पहले से मौजूद था।

शिल्प की शुरुआत

बंगाल में नवाबों के जमाने में इस उद्योग की शुरुआत किस प्रकार हुई, इसके सम्बन्ध में अनेक दिलचस्प कहानियाँ हैं। एक दंतकथा के अनुसार एक दिन बंगाल के नवाब ने कान कुरेदने के लिए कोई चीज मांगी। किसी ने घास की एक तिली लाकर उन्हें दी। किन्तु नवाब को वह चीज पसंद नहीं आयी, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब-ए-नाजिम अपनी शान-शौकत को देखते हुए उस छोटी-सी चीज को कैसे पसंद करता। उन्होंने हाथी दात की कान-कुरेदनी बनवाने की मांग की, जिसके लिए दिल्ली से एक हाथी दात का शिल्पकार बुलाया गया और मुर्शिदाबाद में उसने अपना काम शुरू किया। उस शिल्पकार का नाम अब तक अज्ञात है, पर उभर नवाब-ए-नाजिम का नाम मुजाउद्दीन था, जो मुर्शिदाबाद के बसानेवाले नवाब मुर्शिद कुली जाफर खान का दामाद था। नवाब मुजाउद्दीन शान-

शौकत का प्रेमी था और बहुत-से लोगों का विश्वास है कि उसी ने हाथी दाँत के शिल्पकारों को मुर्शिदाबाद में लाकर बसाया था।

शिल्प का विस्तार

दिल्लीवाला शिल्पकार बड़ा ही चतुर व्यक्ति था। वह सूबे की राजधानी में किसी अन्य व्यक्ति को अपना शिल्प सिखाना नहीं चाहता था। वह अपना दरवाजा भीतर से बन्द करके काम करता था, किन्तु एक हिन्दू भाष्कर छिप कर एक छिद्र से रोज उसके काम करने के तरीके को देखता रहा और उसके शिल्प को समझ लिया। उस भाष्कर का नाम तुलसी खटुम्बा था, जो आगे चल कर हाथी दात शिल्प में पूर्ण निपुण प्रसिद्ध हुआ। उसने



अपने पुत्र को शिल्प की शिक्षा दी, जो बाद में अपने पिता से भी आगे बढ़ गया और नवाब के दरबार में हाथी-दाँत का शिल्पकार नियुक्त हुआ। इस प्रकार मुर्शिदाबाद के हाथी दात के शिल्पकार तुलसी खटुम्बा का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, और जब भी उसका नाम जीभ पर आता है, वे बड़ी विनम्रता से अपने माथे छूकर उसके प्रति सम्मान अभिव्यक्त करते हैं।

तुलसी खटुम्बा का बेटा बड़ा ही मशहूर शिल्पकार हुआ। नवाब ने उसे अनेक प्रकार से संरक्षण दिया था। एक

बार तीर्थयात्रा के सिलसिले में वह उत्तरी भारत गया तो नवाब ने उसके साथ अग्ररक्षक भेजे, ताकि तीर्थ-यात्रा पूरी कर वह मुर्शिदाबाद आ जाये। नवाब यह नहीं चाहते थे कि वह मुर्शिदाबाद छोड़ कर कहीं बाहर जाय, किन्तु उसने किसी तरह तीर्थ यात्रा पर जाने की व्यवस्था कर ली और १७ वर्षों के बाद मुर्शिदाबाद लौट कर आया। घर पर वापस आते ही नवाब ने उसे दरबार में बुलवाया और स्वर्गीय नवाब की प्रतिमूर्ति तैयार करने की आज्ञा दी। तुलसी के बेटे ने तन्मय होकर इतनी सजीव प्रतिमा तैयार की कि उसके शिल्प पर मुग्ध होकर नवाब ने उसे महाजन टोली में एक निवामगृह प्रदान किया और तीर्थयात्रा में जो १७ वर्ष लगे थे उसका पूरा वेतन भी उसे देने का हुक्म दिया। उसके बाद मुर्शिदाबाद जिले में इसी परिवार के वंशधरो तथा सगन्धियों ने हाथी दात शिल्प को जारी रखा। उन्हीं भाष्कर वर्ग के लोगों का इस कारोबार पर एकाधिपत्य है।

दरबारी संरक्षण

उस जमाने में हाथी दात शिल्प समृद्धि के लिए वैभवशाली नवाबों तथा धनी दरबारी रईसों के संरक्षण पर निर्भर था, और इसी वजह से निजामत खत्म हो जाने के बाद धीरे-धीरे उसका भी ह्रास होने लगा। कर्नल क्लाइव ने सन् १७५९ में नवाब मीर जाफर अली खाँ को जब मोम की बनी वस्तुएँ भेंट की तो नवाब ने भी हाथी दात की वस्तुएँ उन्हें प्रदान कीं। इतिहास प्रसिद्ध महाराजा नदकुमार को भेंट की गयी हाथी दात की सज्जा अब भी उनके वंशधरो के पास मौजूद है। मुर्शिदाबाद के किला निजामत में हाथी दात के बने हौदे और पालकी जैसे बड़े-बड़े नमूने अब भी सुरक्षित रखे हैं। वहाँ के इन शिल्पकारों के कौशल की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गयी थी। नवाब नाजिम हुमायूँ ज़ा न (१८२४-१८३८) इंग्लैण्ड के बादशाह विलियम चतुर्थ को नवाबी महल का हाथी दात का बना एक नमूना पेश किया था। वह नमूना स्थानीय शिल्पकार सागर मिस्त्री ने तैयार किया था।

कासिमबाजार के वैभव सम्पन्न दिनों की बात तो दूर रही, सन् १८११ में भी, जब वह नगर बड़ी तेजी से गहन अधकार में डूबता जा रहा था कासिमबाजार अपने रेशम, कोरा तथा हाथी-दात शिल्प के लिए मशहूर था। उन दिनों कासिमबाजार में तथा उसके आसपास हाथी-दात के बहुत-से गिल्पकार रहा करते थे, किन्तु बगाल में कासिमबाजार की मडी का महत्व कम हो जाने के बाद भाष्करों के परिवार बरहमपुर तथा अन्य स्थानों को चले गये। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में मुर्शिदाबाद के हाथी-दात शिल्पकारों को इंग्लैण्ड तथा यूरोप के अन्य शहरों में प्रदर्शनियों के लिए उनके शिल्प के बहुत-से नमूने देने के लिए सरकारी आर्डर मिला करते थे, किन्तु बाद के वर्षों में यह सरकारी खरीद बन्द हो गयी और ऐसी व्यवस्था की गयी कि विदेशों में प्रदर्शन के लिए राजाओं, महाराजाओं, नवाबों तथा रईसों से हाथी-दात की वस्तुएँ उधार लेकर बाहर भेजी जाने लगी। कासिमबाजार के महाराजा के पास ऐसी वस्तुओं का बहुत बड़ा सग्रह था, जिनमें ताजमहल, कुतुबमीनार तथा अन्य ऐतिहासिक भवनों के प्रतिरूप भी थे। छडी के बेट, नेकेलेस, शतरज के मोहरे, चूड़ियाँ, लॉकेट, कुरिग, कधियाँ तथा पौराणिक हिन्दू कथाओं के अनुसार विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियों के प्रतिरूप आदि उन घरों में प्रायः मौजूद रहते थे, जो भारत तथा विदेशों की प्रदर्शनियों में दिखाये जाते थे।

उद्योग का हास

श्री जी सी दत्त ने बगाल में हाथी दात शिल्प पर अपने निबन्ध में १९०१ में लिखा था

“पिछले ३० वर्षों के अंदर मुर्शिदाबाद शहर के समीप मथरा, दौलतबाजार तथा रनसागर गाँवों में यह उद्योग प्रायः मर गया है। तीस साल पहले मथरा गाँव में हाथी दात की वस्तुएँ तैयार करनेवाले ३० परिवार थे और अभी १२ साल पहले तक करीब एक दर्जन परिवार थे। उनमें से बहुत-से तो मलेरिया से मर गये और जो बचे, वे बालूचर (जियागज), बरहमपुर तथा अन्य

स्थानों को चले गये। इन दिनों मथरा में एक भी भाष्कर नहीं रह गया है और जिले भर में कुल मिला कर २५ हाथी दात-शिल्पकार हैं।”

इन दिनों हाथी दात शिल्प उद्योग मुख्यतः खगरा (बरहमपुर) तथा एनाटोली बाग (जियागज) में ही केन्द्रित है। इनमें भाष्कर नामवारी परिवारों की कुल संख्या २० के करीब है और हाल की गणना के अनुसार बूढ़े और जवान कुल ५० शिल्पकार ही यह कार्य करते हैं।

शिल्प की तकनीक

इस शिल्प की सबसे बड़ी विशिष्टता है खुदाई की सूक्ष्मता तथा जोड़ों का न होना। गिल्पकार अपने काम के लिए प्रायः ८० प्रकार के औजारों का उपयोग करता है। मुर्शिदाबादी शिल्प की सब से बड़ी विशेषता यह है कि कोई एक स्वरूप बनाने में कहीं जोड़ नहीं होता, बल्कि देवी का रूप बनावे या हाथी का, हाथी-दाँत के सिर्फ एक



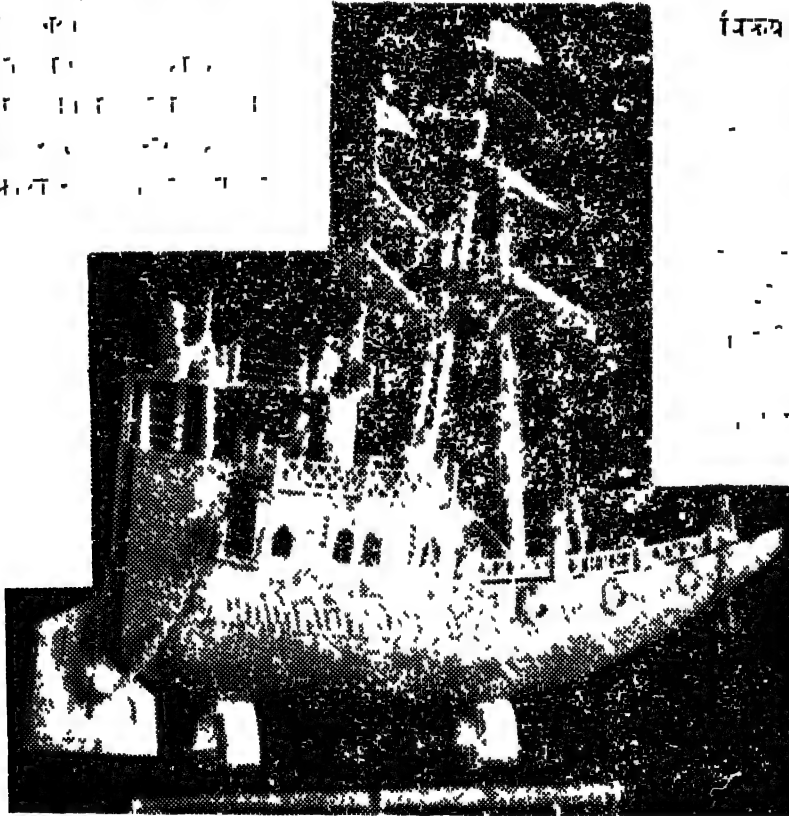
ही टुकड़े को तराश कर बनाते हैं। वे टुकड़े जोड़कर मूर्ति बनाना पसंद नहीं करते। भारतीय और अफ्रीकी, दोनों हाथियों के दाँत वे उपयोग में लाते हैं, पर श्वेत रंग और नम्र होने की वजह से भारतीय दाँतों को अधिक प्रश्रय देते हैं। उनका खयाल है कि अफ्रीकी हाथियों के दाँत कड़े होते हैं और इस कारण छेनी की चोट पर कड़क जाते हैं, किन्तु विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीकी

हाथियों के दात अनेक बातों में भारतीय दातों में श्रेष्ठ है।

दांतों की पूर्ति

उपयुक्त मूल्य पर हाथी-दांतों की पूर्ति तथा तैयार वस्तुओं के विप्रेषण की समस्या इन शिल्पकारों के समक्ष है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग निर्देशालय तथा अखिल भारत दस्तकारी मण्डल ने इन बातों के लिए उनकी सहायता करना शुरू किया है। प्रत्येक हाथी-दात शिल्पकार को अफ्रीकी तथा भारतीय हाथियों के दातों की पूर्ति करने की व्यवस्था की गयी और पिछले वर्षों में दस्तकारी मण्डल ने प्रत्येक शिल्पकार को एक-एक हजार रुपये के दात दिये। किन्तु दातों की कमी की वजह से पूर्ति की मात्रा कम

हो गई।
ऐसा ही है, कि
ऐसा ही है, कि
जो...
अभी...
...



करने के लिए लायसेंस दे। ऐसा भी प्रस्ताव है कि पूर्वी अफ्रीका में दातों का आयात करके पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम लिमिटेड के जरिये उनका वितरण किया जाय। अफ्रीकी हाथी-दातों के आयात करनेवाले ऐसे लोग, जो जमे हुए हैं, बम्बई में हैं। कलकत्ते में उसे मंगा कर शिल्पकारों की पूर्ति करने की व्यवस्था अब तक नहीं है। फिर ऐसा भी है कि बम्बई के व्यापारी खुले बाजार से खरीद करने के बाद ऊँचे दामों पर बेचते हैं। सरकारी दर के मुनाबिक प्रति किलोग्राम हाथी-दात का मूल्य ६० रुपये है, जबकि खुले बाजार में उसकी कीमत ८० रुपये से १०० रुपये के बीच घटती-बढ़ती रहती है।

विप्रेषण की समस्या

ल भारतीय दस्तकारी राज्य उद्योग निर्देशालय १ सालाना २५ हजार हाथी दात की वस्तुएँ है और कभी-कभी को भेजने के लिए खरीद भी करता है। यह सब मिला कर खरीद ४० हजार रुपये से अधिक नहीं होती। ऐसी अवस्था में शिल्पकारों की अपनी वस्तुएँ कम कीमत पर शिल्प वस्तु विक्रेताओं के हाथ बेचनी पड़ती है। इन दिनों बरहमपुर में हाथी-दात शिल्पकारों के

कम से कम ५ परिवार हैं, जो सालाना कारो की, जिन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद लगभग ६० हजार रुपये की वस्तुएँ तैयार करते हैं। अपने पैत्रिक धन्धे को सहेज कर रखा है, सबसे पन्द्रह के करीब और भी परिवार हैं। वे भी करीब बड़ी समस्या है। ६० हजार रुपये की चीजे बनाते हैं। अपनी तैयार वस्तुओं के विक्रय की समस्या मुशिदाबाद के शिल्प- मुशिदाबाद, १३ सितम्बर १९६३

गन्ना उत्पादको का प्रिय मासिक

Sugarcane Herald— **इसका सन्देश**

- गन्ना उत्पादको के उपयोगार्थ अन्वेषण के क्षेत्र में प्राप्त परिणामों का प्रसार करता है।
- केन्द्रीय अनुसन्धानशालाओं तथा राज्य गन्ना अन्वेषण केन्द्रों और विकास केन्द्रों द्वारा की गयी सिफारिशों का प्रचार करता है।
- गन्ना उत्पादको के लिए उपयोगी सांख्यिकीय जानकारी और गन्ने से सम्बन्धित वर्तमान समाचार देता है।
- गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने तथा उसके गुण में सुधार करने के लिए गन्ना उत्पादको को उमकी खेती में तहेदिल से दिलचस्पी लेने के लिए उत्साहित करना है।

आज ही शुल्क भेजिये और पत्रिका की नियमित प्रतियाँ प्राप्त करते रहिये।

शुल्क दर

वार्षिक ३ रुपये एक प्रति २५ नये पैसे

प्राप्ति-स्थल

सेक्रेटरी

इण्डियन सेण्ट्रल सुगरकैन कमेटी

१९-२०, रोहतक रोड

नयी दिल्ली-५

भारत में तिलहन पेराई उद्योग

तरलोचन सिंह

तेल उद्योग के घानी और मिल क्षेत्र में स्पर्धा होने के कारण देश में घानियों की कुल संख्या, पशु गणना के अनुसार १९९१ की ४,४५,३४६ से घट कर १९६१ में २,५०,४५३ हो गयी है। ग्रामीण तेल उद्योग के सामने एक प्रमुख समस्या है घानी तेल की अधिक लागत। तिलहन व तेल की पूति और वितरण के लिए मइकारी समितियों के संगठन के जरिये बिचवानियों से नमस्कार करने में यह लागत किसी हद तक कम की जा सकती है।

तिलहन पेराई भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश में कई किस्म के तिलहनो की खेती होती है, किन्तु उनमें पांच प्रकार के तिलहन कच्ची सामग्री और खाद्य दोनों ही कामों के लिए यह प्रमुख है। उनके नाम हैं मूंगफली, तिल, राई और अलसी तथा अरण्डी। पिछले वर्षों में तिलहनो के समग्र उत्पादन का झुकाव ऊपर की ओर रहा है। उक्त पाँचों किस्मों के तिलहनो का उत्पादन १९५९-६० में ५८ लाख ८५ हजार टन हुआ था। उसमें सुधार हुआ और १९६२-६३ में उत्पादन ६७ लाख ६६ हजार टन हुआ। तालिका १ उक्त पाँच प्रमुख तिलहनो का पिछले चार वर्ष का उत्पादन दिखाती है।

स्थानीय कच्ची सामग्री

भारत संसार में एक प्रमुख तिलहन उत्पादक देश है वर्ष १९६२-६३ के दौरान ४०,९४३ टन तिलहन का और उसकी कृषिक अर्थ-व्यवस्था में तिलहन की फनलो निर्यात हुआ। उस प्रकार हमारे अपने उपभोग के लिए

तालिका १

तिलहन उत्पादन

(हजार टन में)

तिलहन	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३
मूंगफली	३,९४२	४,३९१	४,६११	४,५२०
तिल	३५९	३१६	३७३	४४६
अलसी	४३१	३८९	४४९	४२०
राई व सरसो	१,०४७	१,३३५	१,३१६	१,२७९
अरण्डी	१०६	८९	९९	१०१
योग	५,८८५	६,५२०	६,८४८	६,७६६

६७,२५,०५७ टन तिलहन ही बचे, क्योंकि उम वर्ष कुल उत्पादन ६७ लाख ६६ हजार टन ही हुआ था। खोपरे के अतिरिक्त—जो प्रस्तुत विश्लेषण में शामिल नहीं है—इस अवधि में अन्य किसी तिलहन का आयात नहीं किया गया।

तिलहनो का उपयोग

अधिकांश तिलहन का उपयोग तेल निकालने के लिए

जानेवाले तिलहन के परिमाण के सम्बन्ध में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए धानियों में पेर जानेवाले तिलहन के प्रातिशत्य की मही-मही जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है। तिलहन पेरई उद्योग जाँच समिति ने धानियों तथा शक्ति-बालित मिलों में पेर जानेवाले तिलहन का जो प्रातिशत्य बताया है, वह तालिका ३ में दिया गया है।

तालिका २

भारत में प्रमुख तिलहनो के उपयोग का अनुमानित प्रातिशत्य*

तिलहन	निर्यात	बोआई	खाद्य व घरेलू उपयोग	तेल निस्सारण	योग
मूँगफली तिलहन	० ८	१२ ०	७ ६	७९ ६	१०० ०
राई व सरसो	० १	२ ३	१८ ९	७८ ७	१०० ०
अलसी	नगण्य	१ ५	८ ४	९० १	१०० ०
अरण्डी	नगण्य	५ ०	७ १	८७ ९	१०० ०
	—	५ ९	—	९४ १	१०० ०

*१९६०-६१ को समाप्त होनेवाली त्रिवर्षावधि के दौरान उत्पादन के प्रातिशत्य के रूप में व्यक्त।

स्रोत इण्डियन ऑयलसीड्स जरनल के जुलाई १९६३ के अंक में भारत सरकार के एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एंडवाइजर एन पी चटर्जी का लेख 'सम एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ आयलसीड्स एण्ड देअर प्रोडक्ट्स'।

होता है, जैसा कि तालिका २ से प्रकट है। तालिका २ में प्रमुख तिलहनो का अनुमानित उपयोग प्रस्तुत किया गया है।

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष उपभोग के रूप में कुल तिलहन उत्पादन के एक तुच्छ प्रातिशत्य की ही खपत होती है और १९६०-६१ में प्रमुख तिलहनो का उक्त रूप में उपभोग करीब १८ प्रति शत था।

तेल पेरई

मोटे तौर पर १९६० में कुल ६५ लाख २० हजार टन तिलहन उत्पादन में से करीब ५३ लाख ७२ हजार टन तिलहन पेरई के लिए उपलब्ध थे। उद्योग का फैलाव समूचे देश भर में है और धानियों में पेर

तालिका ३

धानी तथा मिलों में पेर गये प्रमुख तिलहनो का प्रातिशत्य

तिलहन	धानी पेरित	मिल पेरित
मूँगफली तिलहन	२०	८०
अलसी	८३	१७
राई व सरसो	३०	२०
अरण्डी	३७	६३
	—	१००*

* कुछ मात्रा में इसकी पेरई धानियों में भी होती है।

स्रोत भारत सरकार के खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय निर्देशालय के आयलमीड्स इन इण्डिया १९५६-५७ टू १९६०-६१ में उद्धृत 'दि ऑयलसीड्स क्रशिंग इन्क्वायरी कमेटी'।

तालिका ३ में दिये गये प्रातिशत्य के आधार पर अथवा दूसरे शब्दों में यह मानते हुए कि उपलब्ध तिलहनो के अमूमन २७ प्रति शत की पेराई धानियों में और ७३ प्रति शत की मिलों में हुई, तो हम यह कह सकते हैं कि १९६०-६१ में १४ लाख ५३ हजार टन तिलहन धानियों में पेरे गये तथा ३९ लाख १९ हजार टन मिलों में। जैसा कि ऊपर दृगित किया जा चुका है, यह हिमाव इस मान्यता पर लगाया गया है कि धानियों और मिलों द्वारा तेल पेराई की पद्धति वही रही है, जो तिलहन पेराई उद्योग जाच समिति ने दर्ज की है।

धानी व मिलों में तेल उत्पादन

धानियों और मिलों में १९६०-६१ के दौरान २०,१४,४८० टन तेल का उत्पादन होने का अनुमान लगाया जाता है। इसमें से १५,१८,२२० टन मिलों में पेरा गया और शेष अर्थात् ४,९६,३६० टन धानियों में। इस परिमाण का हिसाब तेल के उस प्रातिशत्य तत्व के आधार पर लगाया गया है, जो कानपुर स्थित 'हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजीकल इन्स्टीट्यूट' ने तिलहन पेराई उद्योग जाच समिति के समक्ष पेश किया। भिन्न-भिन्न तिलहनो से मिलों और धानियों द्वारा निस्सारित तेल का परिमाण तालिका ४ में प्रस्तुत है।

तालिका ४

मिलों व धानियों में पेरे गये तेल का कुल परिमाण - १९६०-६१

(हजार टन में)

तिलहन	पेराई के लिए उपलब्ध कुल तिलहन	पेराई		तेल-सम्प्राप्ति का प्रातिशत्य		कुल तेल उत्पादन	
		मिलों में	धानियों में	मिलों में	धानियों में	मिलों से	धानियों से
१	२	३	४	५	६	७	८
मगफली	३,४९५ २३ (७९६)	२,७९६ १८ (८०)	६९९ ०५ (२०)	४०	३५ ५	१,११८ ४७	२४८ १६
तिल	२४८ ६९ (७८७)	४२ २८ (१७)	२०६ ४१ (८३)	४२	३८ ०	१७ ७६	७८ ४४
राई व सरसो	१,२०२ ८४ (९० १)	७५७ ७९ (६३)	४४५ ०५ (३७)	३५	३१ ०	२६४ ७३	१३७ ९६
अलसी	३४१ ९३ (८७ ९)	२३९ ३५ (७०)	१०२ ५८ (३०)	३५	३१ ०	८३ ७७	३१ ८०
अरण्डी	८३ ७४ (९४ १)	८३ ७४ (१००)	—	४०	३६ ०	३३ ४९	—
योग	५,३७२ ४३ (८२४)	३,९१९ ३४ (७२ ९५)	१,४५३ ०९ (२७ ०५)			१,५१८ २२	४९६ ३६

टिप्पणी (१) चूंकि परम्परागत और उन्नत धानियों (वर्षा धानियों) में पेरे गये तेल के परिमाण सम्बन्धी अलग-अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिए कालम छ में इन दोनों प्रकार की धानियों से प्राप्त तेल तत्व का औसत प्रातिशत्य दिया गया है। (२) बोआर्ट के लिए बीज, मानवीय उपयोग और निर्यात के लिए जितने तिलहनो के उपयोग होने का अनुमान है वह कुल तिलहन उत्पादन में से घटा दिया गया है तथा शेष पेराई के लिए उपलब्ध बनाया गया है। (३) कालम २ में कोष्ठक में दिये गये आँकड़े १९६०-६१ के कुल उत्पादन के प्रातिशत्य स्वरूप हैं। (४) कालम ३ और ४ में दिये गये कोष्ठक के आँकड़े मिलों तथा धानियों में पेरे गये तिलहनो का प्रातिशत्य दर्शाते हैं।

आज घानी और मिल विभाग के बीच कड़ी स्पर्धा पायी जाती है। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि देश में घानियों की संख्या बड़ी तीव्र गति से गिरी है। सन् १९५१ की पशु-गणना के अनुसार घानियों की कुल संख्या ४,४५,४३६ थी। सन् १९६१ की पशुगणना के अनुसार उनकी संख्या गिर कर २,५०,४५३ हो गयी।

तेल सम्प्राप्ति

तेल मिलों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण दलील यह दी जाती है कि ये अधिक कार्यक्षम हैं, क्योंकि पेरार्ई में तेल सम्प्राप्ति घानियों की अपेक्षा मिलों में कितनी ही अधिक होती है। तिलहन पेरार्ई उद्योग जाच समिति ने इस पक्ष की गहराई से जाच की। समिति को तेल सम्प्राप्ति के सम्बन्ध में कानपुर स्थित 'हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजीकल इन्स्टीट्यूट' ने जो प्रातिशत्य बताया वह तालिका ४ में दिया गया है।

समिति को दिये गये आकड़ों को ध्यान में रखते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि घानियों और मिलों में पेर जानेवाले तेल की सम्प्राप्ति के सम्बन्ध में अन्तर पर्याप्त अधिक है, फिर भी अभिनव घानी में तेल सम्प्राप्ति पुरानी घानियों से ज्यादा होती है। भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति द्वारा किये गये प्रयोगों के अनुसार मृगफली के मामले में तेल-सम्प्राप्ति का प्रातिशत्य ४१.६४ रहा है।

घानी विभाग के विरुद्ध एक दूसरी दलील यह दी जाती है कि उसमें उत्पादन खर्च अधिक पड़ता है। तिलहन पेरार्ई उद्योग जाच समिति ने बताया कि घानी और मिल तेल उद्योग में तुलनात्मक दृष्टि से औसतन उत्पादन खर्च घानी में नौ से ग्यारह रुपये तथा मिल में पाँच से सात रुपये प्रति मन आता है। इस प्रकार मिल और घानी में उत्पादन खर्च का अन्तर चार रुपये प्रति मन है।

तेलकार को कच्ची सामग्री मिलने से पहले उसे कई स्थानों से हो कर गुजरना पड़ता है। इसमें कुछ अतिरिक्त खर्च भी पड़ता है और घानियों से तेल पेरार्ई करने में जो ज्यादा उत्पादन खर्च आता है, किसी हद तक वह इसके लिए जिम्मेदार है। उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय दृष्टि से यह सिद्ध हो चुका है कि बारगल में किसान द्वारा

उत्पादित तिल जब मद्रास में तेलकार के पास पहुँचता है तो उसे वह २६.२५ रुपये प्रति मन पड़ता है। इसमें करीब ८.२५ रुपये इधर-उधर लाने-ले जाने और वितरण खर्च के पड़ते हैं। इसके दूसरी ओर मध्य प्रदेश की मिल को जो तिलहन २६.२५ रुपये प्रति मन पड़ते हैं उसमें उक्त खर्च लगभग २.२५ रुपये होता है। इसलिए तिलहन तथा तेल को इधर-उधर लाने-ले जाने के लिए सहकारी समितियाँ संगठित कर बिचवानियों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। इससे किसान और उप-भोक्ता का तेलकार के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित होगा तथा मूल्यांतर कम किया जा सकेगा।

लागत खर्च

मिल विभाग का कभी-कभी इस बिना पर भी समर्थन किया जाता है कि वह मूल्य को स्थायित्व प्रदान करता है तथा फसल कटाई के वक्त थोक रूप में खरीद कर किसान को भी सहायता करता है। यह कहा जाता है कि चूँकि तेलकारों के पास भाण्डारीकरण सम्बन्धी सुविधाएँ नहीं हैं, इसलिए वे यह काम नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सहकारों तथा गोदामों का एक जाल-सा बिछा कर यह समस्या हल की जा सकती है।

घानी विभाग के पक्ष में सम्भवतः जो सबसे बड़ी दलील दी जा सकती है वह यह है कि वह हजारों ग्रामीणों को विस्तृत रोजगारी प्रदान करता है। रोजगारी देने की घानी में निश्चय ही अधिक सम्भाव्यताएँ हैं। तिलहन पेरार्ई उद्योग जाँच समिति के प्रतानुसार "भारत की वर्तमान विकासावस्था में यह सबसे महत्वपूर्ण कारण या विचार होना चाहिये तथा घानी उद्योग में अधिक रोजगारी देने की सम्भाव्यता होने की वजह से उसे यदि देश के कुल वानस्पतिक तेलोत्पादन में कुछ कमी हो तो भी, प्रत्येक प्रकार का सम्भव प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है।" चूँकि हमारे यहाँ पूँजी की कमी और श्रम का बाहुल्य है, इसलिए अधिकाधिक संख्या में ग्रामीण घानियों का विस्तार किया जाना चाहिये। लेकिन साथ ही मौजूदा घानियों में, उनके सस्ते और अधिक उत्पादकतावाले नमूनों का निर्माण करके, सुधार करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

नयी दिल्ली १२ मार्च १९६४



गरीब देश, आर्थिक विकास और समाज कल्याण

हाल के वर्षों में 'कल्याणकारी' आर्थिक विचार का विकास हुआ है। उसके साथ ही समाज कल्याण कार्यक्रम सामने आया है। अब तक अर्थशास्त्रियों का ध्यान 'व्यक्ति' के अध्ययन तक ही सीमित रहा है, तथापि, अब 'समाज' के अध्ययन पर जोर है। चूँकि विभिन्न सामाजिक सस्थाओं ने या तो आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया है अथवा मन्द, इस तरह समाज के अध्ययन का अर्थ है विभिन्न सामाजिक सस्थाओं का अध्ययन। यद्यपि सस्थापक अर्थशास्त्रियों (क्लासीकल इकनॉमिस्ट) ने रीति-रिवाज, शासन-प्रणाली, व्यवसाय की स्वतंत्रता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और श्रम विभाजन आदि जैसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक हेतुओं के अध्ययन पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने यह सोचा कि आर्थिक प्रगति में कल्याण वाली बात गौण है, क्योंकि उन्होंने 'व्यक्ति' की आकांक्षाओं का अध्ययन किया 'समष्टि' की आकांक्षाओं का नहीं—उनका सूक्ष्म उपागम मात्र था।

संस्थापित अर्थशास्त्रीय युग के बाद अर्थशास्त्र के सिद्धांत में अनेक परिवर्तन हुए। मार्शल और पिगू के नेतृत्व में जब नवसंस्थापकों (निओ-क्लासिस्ट) ने मानवीय समस्याओं को 'कल्याण' की दृष्टि से देखने की आवश्यकता पर विचार किया तब इसका नवसंस्करण हुआ। रोबिन्स, लरनर, सैम्युअलसन तथा अन्यो ने इनका अनुसरण किया। पेरेंटो ने आर्थिक समस्याओं का समाज कल्याण के सन्दर्भ में अध्ययन करने में अन्य

व्यक्तियों से कहीं अधिक, विशिष्ट, दिलचस्पी ली। काल्डोर और हिक्म ने कल्याण प्राप्त करने हेतु सम्पत्ति का पुनर्वितरण करके समाज को पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सूक्ष्म उपागम से अर्थ-शास्त्रियों को गरीबी और अल्प विकसित गरीब क्षेत्रों के कारणों की छानबीन करने का प्रथम्य मिला।

विकास अध्ययन, गरीब देश व उनकी दुरवस्था

तालिका १ में विश्व की आय के वितरण पर एक दृष्टि डालने से गरीब देशों की दुरवस्था का पता चलता है।

तालिका १

विश्व आय वितरण १९४९

(१९४९ में अमेरिकी डॉलर की क्रय-शक्ति के अनुसार)

	विश्व आय का प्रातिशत्य	विश्व आबादी का प्रातिशत्य	प्रति व्यक्ति आय
उच्च आयवाले देश	६७	१८	९१५
मध्यम आयवाले देश	१८	१५	३१०
निम्न आयवाले देश	१५	६७	५४

स्रोत आर नर्स प्राब्लेम्स ऑफ कैपिटल फोरमेशन

इन अण्डर डेवलप्ड कण्ट्रीज, बासी ब्लेकवेल, ऑक्सफोर्ड, १९५२। (उक्त तालिका में विश्व की वह १० करोड़ आबादी शामिल नहीं है जिसके लिए राष्ट्रीय आय का तखमीना प्राप्त नहीं है, लेकिन वह आबादी निश्चय ही गरीब देशों में है।)

इस प्रकार विश्व की दो-तिहाई आबादी की आमदनी ५५ डालर से कम है। वे अनवरत गरीबी में लोहा ले रहे हैं। तालिका २ में दिये गये आँकड़ों से इन तथ्यों की पुष्टि होती है।

तालिका २

विश्व आबादी और आमदनी का वितरण १९४९

	विश्व आबादी का प्रतिगत्व	विश्व आय का प्रतिगत्व	प्रति व्यक्ति सापेक्षिक आय (विश्व १००)
संयुक्त राज्य अमेरिका	६५	४००९	६२६
पश्चिम यूरोप*	१००	२१५	२१४
सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	८४	११२	१३३
शेष यूरोप	६४	६०	९४
लेटिन अमेरिका	६६	४४	६६
अफ्रीका	८६	२०	२४
एशिया	५२४	१०५	२०

* पश्चिमी, मध्य और उत्तरी यूरोप सहित।

स्रोत इकनामिक डेवलपमेंट एण्ड कल्चरल चान्स (वर्ष १, १७-अक्तूबर १९५६) में एम कुजनेत्स का लेख 'क्वाण्टिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दि इकनामिक ग्रोथ ऑफ नेशन्स।'

इसके अलावा समाज कल्याण की नीतियों के अनुसरण में आबादी का दबाव एक अवरोध का काम करता है, क्योंकि इस दबाव के सामान्यतः तीन रूप होते हैं (अ) अनेक देशों का मुख्य पेशा खेती है, (आ) अधिकांश देशों में ग्रामीण बेरोजगारी है, और (इ) उच्च जन्मानुपात के कारण प्रति प्रौढ़ व्यक्ति पीछे आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही मृत्योनुपात

के घटने से आबादी और भी बढ़ती है। इस प्रकार गरीब देशों में श्रम-शक्ति की भरमार है। चूँकि सीमित भौतिक साधन-स्रोतों के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होने लगता है, इसलिए परिणाम निकलता है विस्तृत पूर्ण और अल्प बेरोजगारी। चूँकि हमारे जैसे देश में अविकाश श्रमिक अकुशल है, इसलिए अतिरिक्त श्रम को अन्यान्य धंधों की ओर मोड़ने के लिए अवसरो का निर्माण करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं।

जैसा कि प्रोफेसर सी वुल्फ और प्रोफेसर एस सी सरफिन* ने कहा है भारत में पूर्ण और अल्प-बेरोजगारी के कारण वार्षिक रूप से कुल इतने मनुष्य-दिन बेकार जा सकते हैं जितने कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समग्र श्रम-शक्ति प्रदान करती है। ऐसा अनुमान है कि कृषिक श्रम-शक्ति का २५ प्रति शत कृषि उत्पादन को बिना कोई आघात पहुँचाये अन्यान्य धंधों में लगाया जा सकता है। गरीब और सम्पन्न देशों की आबादी के स्वरूप से एक दूसरी बात सामने आती है कि गरीब देशों की कुल आबादी में ज्यादा संख्या छोटी उम्रवालों की है और सम्पन्न देशों की अपेक्षा वहाँ आयुमान काफी कम है। अनुमान लगाया जाता है कि १५ वर्ष से कम लोगों की संख्या एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में ४० प्रति शत है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में २५ तथा ग्रेट ब्रिटेन में २३ प्रति शत। नव जात शिशु की औसत आयु भारत में ३२ वर्ष है, जबकि नार्वे में यह औसत ६९ वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका में ६६ वर्ष तथा ग्रेट ब्रिटेन में ६७ वर्ष है। निस्सन्देह गरीब और सम्पन्न देशों में उपभोग का जो स्वरूप है उसका व्यक्तियों की आयु पर निश्चित प्रभाव पड़ता है, और समाज व्यक्तियों से ही बनता है। तालिका ३ में यह सहसम्बन्ध प्रस्तुत किया गया है।

* सी वुल्फ और एस सी सरफिन कैपिटल फोरमेशन एण्ड फोरेन इन्वेस्टमेंट इन अण्डर डेवलपिंग एरियाज, सिरैक्यूस यूनिवर्सिटी प्रेस, सिरैक्यूस, १९५५, पृष्ठ १३-१४।

तालिका ३

चुनिन्दा देशों में प्रति व्यक्ति कैलोरी : १९५४-१९५५

देश	प्रति दिन कैलोरी	प्रति दिन प्रोटीन, ¹ (ग्राम में)
सम्पन्न देश		
आस्ट्रेलिया	३,०४०	९१
कनाडा	३,१२०	९८
डेन्मार्क	३,३३०	८९
फ्रॉम	२,७८५	९६
पश्चिम जर्मनी	२,९४५	७७
न्यूजीलैण्ड*	३,२९०	९९
नार्वे	३,१४०	९१
स्वीडन	२,९७५	८७
ग्रेट ब्रिटेन	३,२३०	८६
संयुक्त राज्य अमेरिका	३,०९०	९२
गरीब देश		
ब्राजील @	२,३४०	५७
चिली @	२,४९०	७७
मिश्र*	२,३९०	६९
यूनान	२,५४०	८०

भारत*	१,८४०	५०
पाकिस्तान*	२,०२५	५०
पेरू @	२,०८०	५४
रोडेशियन न्यासालैण्ड ¹	२,६३०	८१
टर्की . . .	२,६७०	८६
वेनेजुएला†	२,२८०	५९

*१९५३-१९५४, @१९५२, †१९५१

स्रोत इयरबुक ऑफ फूड एण्ड एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स,
१९५५, फूड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन,
१९५६, तालिका ८०।

इस प्रकार अपौष्टिक और अपर्याप्त आहार की समस्या हल करना जनकल्याण सम्बन्धी प्रयासों का अंग है। चूँकि विभिन्न देशों के आहार की पृष्ठभूमि में रीति-रिवाज, परम्परा, स्वभाव आदि का हाथ रहता है इसलिए इसमें भी सामाज्यार्थिक हेतुओं की बात आ जाती है। अतएव सस्यात्मक बाधाएँ दूर करनी होंगी, ताकि सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में समा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज कल्याण की नीति को आर्थिक विकास की नीति के साथ प्रभावशाली रूप में जोड़ना होगा तथा यह कि सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

मदुराई : १६ नवम्बर १९६३ —ने. सु. तिरुवेकटाचारी

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और महिलाएँ

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की स्थायी अर्थ-व्यवस्था को कृषिक ग्रामीण पद्धति पर आधारित करना होगा। जैसा कि हाल ही में प्रोफसर पी जे फॉक्स ने कहा है, “विश्व की एक महानतम विभूति मोहनदास गांधी ने महसूस किया कि कृषिक ग्रामीण पद्धति में एक स्थायित्व है जो औद्योगिक शहरी व्यवस्था में नहीं है। जिस ब्रिटेन में केवल पाँच प्रति शत कर्मी-शक्ति ही खेती में लगी है, उसका क्या भविष्य होगा, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। मोटे तौर पर

फ्रांस की ५० प्रति शत कर्मी शक्ति कृषि में लगी है। वह इस सुसन्तुलन को अल्जीरिया में औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करके बदलने के लिए बुरी तरह पागल है। किस प्रातिशत्य में कर्मी शक्ति कृषि में रहे, यह एक ऐसी महान समस्या है जिस पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। ब्रिटेन में इस पर ध्यान दिये जाने की बहुत कम गुंजाइश है—उसकी अर्थ-व्यवस्था बुरी तरह असन्तुलित है—लेकिन इस सम्बन्ध में सर्वाधिक गुंजाइश है भारत में।”

दीर्घ स्तरीय औद्योगीकरण के अन्तर्गत सभी देशों की आर्थिक प्रगति समान गति से नहीं होती और चन्द देश दूसरे देशों से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तब जिन देशों में औद्योगीकरण हो चुका होता है वे अपने उद्योगों के लिए जिन क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त होता है उन पर नियंत्रण करना या रखना चाहते हैं। अधिकाधिक भूमि पर नियंत्रण करने के इस बनावटी रूप से निर्मित आवश्यकता और आकांक्षा से युद्धों को प्रश्रय मिला है।

प्रकृति ने इस धरा पर चीजों की बनावट सम्भवतः कुछ इस ढंग से की है कि समग्र मानवता एक है। पृथ्वी के एक हिस्से में कहीं अगर सोना है तो दूसरे भाग में तेल है। किसी एक क्षेत्र की जलवायु खाद्यान्नों की फसल के लिए उपयुक्त है तो दूसरे की मसालों के लिए और किसी तीसरे की रेशों की फसल के लिए। कहा जाता है कि धरती की कुल सम्भाव्य क्षमता स्रोत (खाद्यान्नों, फसलों, खनिजों आदि के स्रोत) इतने है कि वे वर्तमान विश्व जन-संख्या से दुगुनी आबादी के लिए भी कम नहीं पड़नेवाले हैं। लेकिन व्यावहारिक स्थिति यह है कि सभी प्रकार की भूमि पर खेती नहीं की जा सकती। कुछ दूरस्थ प्रदेशों से उत्पादन को लाना—ले जाना भी असम्भव अथवा अलाभदायक है। और, न ही आबादी का दीर्घ स्तरीय स्थानान्तरण शक्य है।

आदिवासी अर्थ-व्यवस्था

यह एक तथ्य है कि राजनैतिक दृष्टि से आजाद होने और वैसा बने रहने के लिए किसी देश के लिए यह आवश्यक है कि वह आर्थिक दृष्टि से भी आजाद हो। और, आर्थिक आजादी के लिए यह आवश्यक है कि छोटी-छोटी आत्मनिर्भरक सामाजिक इकाइयाँ हों। आज भी भारत के कई स्थानों में ऐसी आदिवासी अर्थ-व्यवस्था* पायी जाती है (जैसे मध्य प्रदेश में) कि वह इस ढाँचे

* टी एस नाग - ट्रायबल इकनॉमी।

के काफी समीप है। आज आदिवासी अपनी आवश्यकता के खाद्यान्न पैदा करते हैं अथवा इकट्ठा करते हैं और अपने घर बनाने के लिए उन्हें वास्तव सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर से उन्हें कुछ नमक, कपड़ा, तेल, साबुन, आदि जैसी चीजें ही खरीदनी पड़ती हैं। अनेक हिस्सों में बदलौन पद्धति जारी है, और कपड़े आदि के बदले में कोई वन्य उत्पादन अथवा अन्न दिया जाता है। आदिवासी महिलाएँ बाजार में कुछ वन्य उत्पादन, छाल अथवा रेशा आदि लाती हैं और मसाले, तेल, साबुन आदि उनके बदले में खरीद लेती हैं।

स्थानीय जनता का आर्थिक विकास आवश्यक रूप से ही उस क्षेत्र के प्राकृतिक साधन-स्रोतों के उपयोग पर आधारित होना चाहिये। वसी प्रकार उत्पादन का सगठन भी—उदाहरणार्थ सहकारी समितियों के जरिये—वन्य उत्पादनो पर आधारित होना चाहिये। उपयुक्त कुटीरो-द्योगों का विकास ही समस्या का एक मात्र समाधान है। सरकार तथा सामाजिक सगठनों ने इस आधार पर कुछ काम शुरू किया है, लेकिन और भी विकास करने की काफी गुंजाइश है। हमारे देहातों और आदिवासी क्षेत्रों में जीवन का जो समरस स्वरूप है वह सुरक्षित रखा ही जाना चाहिये। यद्यपि जीवन की चन्द परमावश्यक सुविधाओं—खास कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी—के क्रमिक समावेश से इन्कार नहीं किया जा सकता, तथापि उनका आर्थिक ढाँचा आवश्यक रूप से ही आत्मनिर्भर इकाइयों पर आधारित होना चाहिये।

महिलाओं की भूमिका

गाँवों में स्त्री आदमी की सभी व्यावसायिक गतिविधियों में—प्रधान रूप से कृषि तथा कटाई, बुनाई, कुम्भकारी आदि जैसी दस्तकारियों के क्षेत्र में—उसकी सगिनी और सहकर्मिणी रही है तथा है। देग की आदिवासी महिलाओं ने जो भूमिका निभाई है वह सर्वविदित नहीं रही है। इसका कारण यह है कि आदिवासी दूरस्थ स्थानों में रहते हैं जो आवागमन के समुचित साधनों से शेष भाग के

माय जुड़े हुए नहीं हैं—संचार के अन्य साधनों की भी कमी है। इनमें कई कल्याणकारी परियोजनाएँ तथा विकास कार्यक्रम शुरू करने से इनमें और देश के अन्य लोगों में शान-शान नये सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं। यह सम्बन्ध यद्यपि आदिवासियों की भलाई के लिए है, तथापि ऐसी बात नहीं कि उसके बुरे प्रभाव नहीं पड़े हैं। निहित स्वार्थियों ने इन आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का शोषण के नये स्रोतों के रूप में उपयोग किया है।

हैदराबाद में हाल ही में सम्पन्न एक सम्मेलन में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि आज एक आदिवासी और बाहर के आदमी के बीच जो सम्बन्ध है वह मात्र शोषक और गोपित का है। यद्यपि यह बात पूर्णतः सही नहीं है तथापि इसमें बहुत कुछ सत्य है। साहूकार आदिवासियों में बहुत सस्ते में वन्य उत्पादन खरीदते हैं। इन क्षेत्रों में प्रचलित माप-तौल के साधन पुराने हैं। महाजन साधारण साबुन अथवा अन्य कोई बहुत सस्ती चीज अत्यधिक ऊँचे दामों में बेचता है। पैसा-उबारी अथवा दूर बैठे जमींदार की जमींदारी पहले कभी भी आदिवासी क्षेत्रों में नहीं रही है। वह आज इन सामाजिक इकाइयों के स्थापित्व में और भी कुठाराघात कर रही है। यद्यपि आदिवासियों को शिक्षा देना आवश्यक है, पर निष्ठावान अथवा मुप्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं।

श्रम विभाजन

ये आदिवासी जिन जंगलों में रहते हैं वहाँ उपयोगी पेड़-पौधों और पशु उत्पादनों की भरमार है। वे इन उत्पादनों का अनेक कामों में इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी महिलाएँ कठोर परिश्रमी और ह्यूट-पुष्ट होती हैं। जिन स्थानों पर हल का प्रयोग नहीं होता वहाँ ये महिलाएँ फावर्ड में जमीन की खुदाई तक करती हैं। साधारणतया वहाँ श्रम विभाजन है। महिलाएँ फल संग्रह, मछली पकड़ने आदि जैसे अपेक्षाकृत आसान काम करती हैं। आदमी कन्द-मूल खोदते हैं। (कभी-कभी इसके लिए दो-तीन

फुट गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है।) इसके अलावा मरद जहाँ पेड़ गिराने, उन्हें जलाने और शिकार जैसे काम करेगा वहाँ औरत बोआई तथा कटाई जैसे हलके खेती सम्बन्धी काम और विभिन्न प्रकार के घरेलू कामों में मदद देगी। सीधी-सादी बुनाई करना, रस्सी बाँटना और टोकरियाँ बनाना कुछ ऐसे खास-खास काम हैं। ये ही तो मुख्यतः वे काम हैं जिनमें अन्तर्निहित प्रतिभा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा फुरसत के समय महिलाएँ और भी अनेक काम कर सकती हैं।

दुर्भाग्य से कुछ लोग आदिवासियों को जंगली और अनुगामनविहीन, असभ्य तथा अभद्र समझते हैं। यह बात सही नहीं है। साधारणतया वे बहुत-ही अनुगमित व्यक्ति हैं। शिष्टता, गलत और सही के सम्बन्ध में उनके अपने माप-दण्ड हैं। आदिवासी महिलाएँ कर्तव्यनिष्ठ हैं और वे अपने समाज के अनुशासन का कड़ाई से पालन करती हैं। अपनी परम्पराओं में उनका अटल विश्वास है।

इस प्रकार की अनुगमित महिलाओं को किसी प्रकार के प्रशिक्षण-सह-प्रत्यक्ष कार्य में संगठित करना कोई असम्भव नहीं होना चाहिये। हो सकता है कि प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयाँ आयें। जरूरत है उनमें विश्वास भरने और उनकी शक्ति को किसी खास दिशा में लगाने की।

महिलाओं के सक्रिय सहयोग में कुटीर उद्योगों का मगटन एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। हमारे देश में जहाँ अनादि काल से जीवन की सभी दिशाओं में धार्मिक अथवा सांस्कृतिक मूल्यों का बोलबाला रहा है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बुनियादी सामाजिक इकाई, घर की समग्रता बनायी रखी जाय। भारतीय महिलाएँ—यद्यपि भूतकाल में अशिक्षित—कभी भी अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं रही हैं, फिर चाहे वह भूमिका घरेलू क्षेत्र में हो अथवा राष्ट्र की आत्म की रक्षा करने के क्षेत्र में। आज शिक्षा और विभिन्न प्रकार के कामों के विस्तार के साथ महिलाएँ, यहाँ तक कि घर से बाहर के क्षेत्र में भी पदार्पण कर चुकी हैं और अनेक नागरिक तथा प्रति-

रक्षात्मक कामों में हाथ बटा रही हैं। तथापि, भारत के गाँवों में महिलाओं की सख्या को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करनेवालियों की सख्या तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। इस सम्बन्ध में भिन्न मत भी हैं कि दफ्तरो में काम करनेवाली महिलाओं का हमारे सामाजिक स्वरूप तथा परिवार के स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

पुरुष पहले से ही गाँवों से शहरों में औद्योगिक श्रम, सड़क निर्माण तथा अन्य काम-धंधों की ओर खिंचे जा रहे हैं। यदि महिलाओं को भी इसी ओर घसीट लिया गया तो इस प्रकार की घटनाएँ सामने आयेगी—गाँवों का शून्य हो जाना, घरों की वदली शहरीकरण,

शहरों में आवादी का जमाव, गन्दी वस्तुओं का बस जाना, ऊँची कीमते और वस्तुओं की कमी, यहाँ तक कि घर-वार का टूट जाना अथवा बेघरवार हो जाना और अनेक ऐसी सामाजिक बुराइयों का खडा हो जाना जिनका कोई अन्त नहीं।

अतएव यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ग्रामीण महिलाओं को उनके गाँवों में ही कर्मी वर्गों में संगठित किया जाय। इससे इस जन-शक्ति के परिपूर्ण उपयोग, जगलों के प्राकृतिक साधन-स्रोतों के उपयोग और एक अविक स्यायी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना को प्रश्रय मिल सकता है।

कलकत्ता १२ फरवरी १९६४

—सत्या कुमारी

धान की हाथ कुटाई व सेलीकरण

चावल खानेवाले पूर्व के सभी देशों में बेरीबेरी नामक एक रोग होता है। तथापि, भारत में मलाया, हिन्द चीन, थाईलैण्ड, जापान और फिलीपाइन्स की अपेक्षा यह बीमारी सदैव ही कम रही है। भारत में स्थानिक रोग के रूप में यह उत्तर-पूर्वी समुद्र तट के एक छोटे क्षेत्र—गजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा, गुन्तूर और नेल्लूर जिलों सहित उत्तरी सरकार के इलाके—तक सीमित है। देश के दूसरे हिस्सों में यह बीमारी आकस्मिक रूप से ही होती है। यद्यपि जिन क्षेत्रों में यह बीमारी फैलती है, उनकी जनसख्या भूतपूर्व के मद्रास की कुल जनसख्या की ३० प्रति शत है, तथापि बेरीबेरी की बीमारी ९५ प्रति शत इन्ही क्षेत्रों में ही होती है। मद्रास में बेरीबेरी की बीमारी होनेवाले क्षेत्रों और चावल खानेवाले अन्य क्षेत्रों के लोगों के भोजन की प्रकृति में यह आवश्यक फर्क है कि जहाँ मद्रास के पहले के क्षेत्रों में कच्चा चावल पका कर खाया जाता है वहाँ उसके (मद्रास) वाकी क्षेत्रों में और बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा में आम तौर पर उसना चावल पका कर खाया जाता है। चावल से बेरीबेरी रोग फैलने

के कारण इस बात से स्पष्ट होते हैं कि उसना चावल में विटामिन बी१ होने से वह कच्चे चावल से श्रेष्ठ होता है।

खोज

मलय राज्यों में फ्लेक्थर (Fletcher) ने १९०७ में, फ्रेजर (Fraser) और स्टेण्टन (Stanton) ने १९०९ में तथा चेम्बरलेन (Chamberlain) ने १९११ में फिलीपाइन्स द्वीप समूह में आहार से बेरीबेरी रोग होने के बारे में प्रयोग किये। तब १९३२ में अक्रायड (Aykroyd) की खोजें सामने आईं। ब्रेडन (Braddon) ने मलय सघ के राज्यों में खोज कार्य करते हुए यह पता लगाया कि मलाया में चीनी और तमिल प्रवासियों की बेरीबेरी रोगों की ग्रहणशीलता बहुत भिन्न थी। चीनी लोग इस रोग से बहुत अधिक ग्रस्त थे जबकि तमिल भाषियों पर इसका प्रभाव इसलिए नहीं पडा कि वे धान की भूसी उतारने से पहले उसे उमना कर लिया करते थे।

इन खोजों से धान को उमना करने के रिवाज की प्राचीनता की जानकारी होती है। सैकड़ों वर्ष पहले

मलाया जाते हुए तमिल जन दक्षिण भारत में धान को उसना करने के तरीके का ज्ञान भी अपने साथ ले गये होंगे। तमिल भाषा में भोजन पकाने के दो शब्द हैं। वे हैं पोगल (पर्याप्त भर पानी से भोजन पकाना), और वडितल (अतिरिक्त पानी नितारना)। पोगल हमेशा कच्चे चावल से सबधित है और वडितल उसना चावल से। प्राचीन तमिल साहित्य में उसना चावल के उपयोग के बारे में एक अप्रत्यक्ष जिक्र इस प्रकार है

चोरु अक्कीय कोलुकजि यारूपोल परतोलुकि
—पहिनप्पालै (४४-४५)

इस उद्धरण में यह कहा गया है कि यात्रियों और साहित्यकारों को मन्दिर के समीप सदाव्रत (मडम्ब) बँटा जा रहा था। वहाँ से भोजन पकाने के बाद जो पानी फेंक दिया गया था उसकी नदी बह रही थी। वहाँ गाय और बैल पानी पीने के लिए आये और बैलों आदि में लड़ाई हो गयी। इस उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सदाव्रत बँटने के इन स्थलों पर उसना चावल का उपयोग किया गया था।

उमना करने के बारे में एक दूसरा जिक्र है
देल्ले पुलुकल नेल्लिन् पोरी बीलोत्तेन्न नुक्कुलिप्पुहिन्
मगकालईल —ऐकुरु नुरु (१४३)

इस कविता में यह बताया गया है सफेद उसना धान से चावल की भूसी (पोरी) अलग की गयी।

एक दूसरी कविता में कहा गया है

अकनुकर विथन्मुदुतु चुडर नुत्तन मडनोक्कि नेरिल्लै
मकलिर उमाकुणा कवरु कोलियेरित
—पहिनप्पालै (२०-२५)

इसमें त्रियो द्वारा अपने घरों के सामने उसना धान को मुखाने का वर्णन है। वे उन मुर्गों को भगा रही हैं जोकि उनका धान खाने के लिए आ टपके थे। सेलीकरण यानी उमना धान के बारे में एक दूसरा प्रसंग इस प्रकार है

अरि चेतुणकिय पेळ्चेनेल्लिन तेरिक्कोल आरिशि
तिरल नेड पुलनक्कल —पेरुपाणाहुप्पडै (४७३-४७४)

इस कविता में लाल रंग के उसना धान का वर्णन है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि आदि काल से ही धान को उसना करने का रिवाज प्रचलित है।

त्रिनेन्द्रम् २ जनवरी १९६४

—तो. मी. सुन्दरम

इस तरह के प्रखर बुद्धिवाले लोगों के सम्बन्ध में दूसरी कठिनाई यह है कि उच्च स्तर के प्रज्ञावान अधिक नहीं हैं। १९० के प्रज्ञा स्तर पर आर्किमिडीज, न्यूटन और गॉस को गिना जा सकता है, जिनका प्रादुर्भाव प्रायः ५०० वर्षों के बाद ही हुआ करता है। आबादी में हाल की वृद्धि तथा खोज के क्षेत्र में जानेवाले लोगों के प्रातिशत्य में वृद्धि से ऐसे लोगों की ज्यादा गिनती हो सकती है। (किसी भी जमाने में मौजूद वैज्ञानिकों का ९० प्रति शत आज भी जीवित है।) १८० का स्तर डार्विन, फ्रायड, शॉ, बट्ट्रेण्ड रसेल, पर्सी त्रिजमैन, लिनस पालिंग का। जब हम १७० पर पहुँचते हैं, तब सिर्फ अमरीका में ही करीब ३०० ऐसे लोगों को पाते हैं, और १६० पर करीब ५०००, १५० पर १ लाख तथा १४० पर १० लाख।

—लाइफ (२४ फरवरी १९६४) में जान रेडर प्लॉट का लेख
दि कमिंग एक्सप्लोजन इन ह्यूमन इण्टेलिजेन्स।

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए 'ग्रामोद्योग' इलाहाबाद रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ में प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल एस्तेसिपेटेड एडवर्टाईजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ५०५, तारदेव, आर्थर रोड, बम्बई-३४।
वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ नये पैसे।

जवाहरलाल नेहरू

इस आकस्मिक घटना से हम सब स्तम्भित होकर रह गये, इसने एक महान व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि एक युग का अंत कर दिया। जवाहरलालजी के कदमों की वह चुस्त गति और उनका वह प्रसन्न मुखारविन्द अब देखने को न मिलेगा और न अब सुनने को मिलेगी उनकी वह ओजस्वी वाणी, जिसमें माधुर्य के साथ पूर्ण दृढ़ता का भी समावेश रहता था। मानव जीवन की यही गति है, 'जो आया है, सो जायेगा।' फिर भी, हमें इस विपत्ति के मुकाबले के लिए अपने को तैयार करना ही पड़ेगा।

जवाहरलालजी की गणना अमरात्माओं में होगी। विश्व इतिहास के लम्बे दौर में अनेक राष्ट्र विदेशी आधिपत्य से मुक्त हुए, और विभिन्न देशों में राज्याधिपति के पद पर राजा, राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति विशेषों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। स्वातंत्र्य-संग्राम के दौरान प्रदर्शित निर्भीक नेतृत्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को विश्व राष्ट्र मण्डल की अगली पक्ति में ला खड़ा कर देनेवाले उनके प्रेरणादायक राज-कौशल के कारण, जवाहरलालजी का

स्थान ऐसे सर्वोच्च महापुरुषों की श्रेणी में रहेगा। आज सारा संसार जवाहरलालजी को एक ऐसी हस्ती मानता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मेल-जोल और शांति के लिए स्थायी योगदान दिया है।

हम लोगों के लिए भारतीय मानवता के साथ अपने पूर्ण एकात्म्य की वजह से जवाहरलालजी इतने प्रेम और श्रद्धा के भाजन हो गये थे कि ससार के इतिहास में इने-गिने नेताओं को ही ऐसा सौभाग्य मिला होगा। प्रधान मंत्री के पद पर आसीन होने के वर्षों पहले ही जवाहरलालजी ने देश के समस्त नर-नारियों को सुखद जीवन व्यतीत करने तथा प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होने का अवसर प्रदान करने में सहायता करने का अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे चाहते थे कि हम नयी समाजवादी तथा जनतांत्रिक समाज-व्यवस्था के लिए अग्रसर हों।

जवाहरलालजी जनतांत्रिक प्रवृत्तियों के प्रतीक थे। सहिष्णुता की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे सभी के प्रति चितनशील रहते थे और दूसरों के विचारों

का सम्मान करते थे। यही कारण है कि वे करोड़ों भारतीयों के इतने प्रिय पात्र बन गये। इसके साथ ही उनमें वह महान व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति थी कि असंख्य लोग बर-बस उनकी ओर खिंचे चले आते थे, जिनके साथ उन्होंने बिना किसी प्रयास के दिली सम्पर्क स्थापित किया। युग-युगान्तर में ऐसे इने-गिने व्यक्ति ही हुए हैं, जिनमें ये

गुण एक साथ पाये जाये। जवाहरलालजी में ये सारी विशेषताएँ भरपूर मात्रा में थी, और यही कारण है कि उनमें साधुता व महानता का अनुपम समिश्रण जीवन-पर्यन्त रहा।

—वैकुण्ठ ल. मेहता

[‘आकाशवाणी’, बम्बई से २८ मई १९६४ को प्रसारित श्रद्धांजलि का मूल।]



जवाहरलाल आज हमारे बीच नहीं हैं। जब से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, तब से लेकर अपने अन्तिम क्षण तक वे प्रकाश में रहे और सार्वजनिक आकर्षण के विषय बने रहे। जीवन के समान ही, काल की गोद में जा कर भी उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे भारत के आराध्य थे। हम उनके इतने सन्निकट रहे हैं कि भारत के इतिहास में उनके स्थान और राष्ट्र विकास में उनके योगदान का ठीक से मूल्यांकन हम नहीं कर सकते।

नेहरू एक माने हुए राजनीतिक नेता, एल महान लेखक और मानवता के एक महान उपासक थे। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और

राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग का विकास करने की दिशा में उन्होंने जो प्रयत्न किये, विश्व के प्रमुख राजवेत्ताओं ने इस सम्बन्ध में उनकी प्रशंसा की है। दो भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिनिधि श्री ख़ुश्चेव और राष्ट्रपति जान्सन, दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नेहरू की भूमिका के सम्बन्ध में एकमत हैं तथा दोनों का ही आवाहन है कि युद्धविहीन विश्व के विचार को साकार रूप देना ही नेहरू का असली स्मारक होगा।

भारतीय जनता को उन्होंने आवाज दी। उन्होंने स्वतंत्रता-राजनैतिक व आर्थिक दोनों ही प्रकार की-संग्राम में एक हो कर

अपनी सारी शक्ति लगा देने के लिए उसे प्रेरित किया। भारत के आर्थिक विकास के स्वरूप पर भी नेहरू का प्रभाव उतना ही गहन है, जितना कि राजनीतिक विकास पर। कुछ तो यहाँ तक महसूस करते हैं कि अन्तिम विश्लेषण से यह सिद्ध हो सकता है कि उनकी आर्थिक नीतियाँ राजनीतिक नीतियों से अधिक महत्वपूर्ण थी। तथापि, इन दोनों पहलुओं को अलग-अलग करके देखना सही नहीं होगा; क्योंकि दोनों एक-दूसरे से निकटतम रूप से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र के कट्टर समर्थक होने के कारण वे आर्थिक असमानता को सह नहीं पाते थे, जोकि निश्चय ही मानवीय दुःखों को जन्म देती है। इतिहास और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तथा एक सक्रीय राजनीतिज्ञ होने के नाते वे यह अच्छी तरह जानते थे कि वैसी व्यवस्था से आर्थिक समानता सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जोकि व्यष्टि और साथ ही समष्टि के अग के नाते व्यक्ति की प्रभुता को मान्यता न दे।

नेहरू ने बिल्कुल ठीक विश्लेषण किया था कि आधुनिक युग में भारत के दुःख-दारिद्र्य का कारण है तकनालॉजी और आर्थिक क्षेत्र में सापेक्षिक दृष्टि से उसका पिछड़ा हुआ होना। अतः वे देश में प्राविधिक और आर्थिक विकास के युग की प्राप्ति का दृढ़तापूर्वक समर्थन करते थे। यही वह

मुख्य कार्य था जिस पर उन्होंने सरकार के प्रधान और देश के नेता के रूप में अपना ध्यान केन्द्रित किया। वे देश में आर्थिक आयोजन के सम्बोध के प्रणेताओं में से थे। सन् १९३८ में ही कांग्रेस अध्यक्ष (तब राष्ट्रपति) श्री सुभाष चन्द्र बोस ने राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष श्री नेहरू थे। इस समिति के प्रयासों के फलस्वरूप ही आयोजन के विचार का प्रसार हुआ और एक तरह से इसने आदर भी प्राप्त किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद ही जब राष्ट्रीय सरकार ने योजना आयोग का गठन किया तो उसके अध्यक्ष के लिए स्वभावतः नेहरू को ही चुना गया। तथापि, नेहरू अन्धविश्वासी बिल्कुल नहीं थे। वे देश के उद्योगीकरण के लिए बहुत उत्सुक थे, परन्तु देश के उद्योगीकरण की राह में जो जबरदस्त सीमाएँ थी, उनसे भी वे अनभिज्ञ नहीं थे और जानते थे कि इसमें (उद्योगीकरण में) काफी समय लगनेवाला है। इस बीच लाखों बेकारों को जीविका देने के लिए कुछ तो करना ही था। अतः वे ग्रामीण विकास और ग्रामीण उद्योगीकरण के भी उतने ही पक्ष में थे, जितने कि उद्योगीकरण और सगठन के।

नयी दिल्ली में २ फरवरी १९५३ को अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था, “भारत

जैसे देश में बड़े उद्योगों का हम कितना भी विकास क्यों न करें, ग्राम उद्योगों के विस्तार की फिर भी गुंजाइश है ही। सवाल है देश की व्यापक आर्थिक रचना में छोटे उद्योगों का अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने का। हम सभी खादी और दूसरे छोटे उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, किसी 'दिखावे' के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम ठोस परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। फिर भी, अगर कोई देश अपनी आजादी कायम रखना चाहता है तो उसे बड़े पैमाने के उद्योग-धंधों का विकास करना ही होगा, बड़े उद्योगों की जरूरत है और वे राज्य-मिलिकित के अन्तर्गत तथा राज्य द्वारा नियंत्रित होने चाहिये।"

श्री नेहरू ने आगे कहा था, "निम्नोपार्थक्य हमारा यह मानना है कि देश के आर्थिक विकास में छोटे उद्योग काफी मदद दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी सबसे कठिन समस्या है बेकारी का सवाल हल करने की और इसे हल करने में छोटे पैमाने के तथा गाँवों के उद्योग मिल कर बहुत सहायक होंगे। हम कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बातें करते हैं, पर कल्याण-

कारी राज्य तो वह होता है, जहाँ हर नागरिक एक हिस्सेदार होता है, लोगो को काम न मिला तो कल्याणकारी राज्य कैसा? बेकार के लिए कल्याणकारी राज्य का कोई मतलब नहीं है। मैं बड़े धंधों (उद्योगों) और ग्राम उद्योगों में संघर्ष का कोई कारण नहीं देखता ... बशर्ते दोनों के बीच उपयुक्त समन्वय हो।"

छोटे उद्योगों और अदने आदमी के पक्ष में अब हम उनकी शक्तिशाली तथा प्रेरणादायक आवाज नहीं सुन सकेंगे। फिर भी, यह तथ्य कि जवाहरलाल नेहरू जीवन-पर्यन्त उत्पीड़ितों के उत्थान के लिए जूझते रहे और आयोजित सामाजार्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंगस्वरूप राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकेंद्रित विभाग के विकास को उन्होंने जबर्दस्त व्यक्तिगत समर्थन प्रदान किया, निश्चय ही क्षेत्र में काम करनेवाले सभी व्यक्तियों को प्रेरणा देता रहेगा और उनके प्रयासों को शक्तिशाली बनाता रहेगा।

अपने दिवंगत नेता की पावन स्मृति में हम सर नवाते हैं।

—सुभाष चन्द्र सरकार

बम्बई : १ जून १९६४

दशम वर्ष • जून १९६४ • मन्मथ अंक



	पृष्ठ
सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर	५८३
गाँव और शहर	—वैकुण्ठ ल. मेहता ५९९
केरल में सहकार और कृषि उत्पादन	—कृ. श्रीकण्ठन नायर ६०३
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण	—चित्तूरी वेकट राघवुलू ६०८
गुजरात के तीन गाँवों में ग्राम-नेतृत्व	—यशवन्तसिंह जाडेजा ६१४
मिट्टी की अभिव्यक्ति और अपारदर्शी	—जामेश्वर गो. श्रीखण्डे और
काचन चन्द प्रयोग	यशवंत वि. खेर ६२१
अन्नोपभोग और घटिया से बढ़िया अनाज की	—तण्डलम स्मो. यशवंत और
ओर एक अध्ययन	रा राजगोपालन ६२३
हरसूद सामुदायिक विकास खण्ड का सर्वेक्षण	
और आयोजन	६३१
तेल उत्पादक सहकारों को सुझाव	—त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्ति ६३७
विचार-विमर्श	
एक राजस्थानी गाँव में कुम्भकारी उद्योग	—खेमराज पिछोलिया ६४१
अभिनव भेड़-पालन	—गुलजार सिंह ६४२
कश्मीरी गब्बे की कहानी	—इन्दर मो मटनागर ६४३

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोदय', इलाहाबाद, बम्बई-९६ से मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थशास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इलाहाबाद, बम्बई-९६ (ए एस्) के पते पर भेजे। टेलीफोन नं. ५७१३२९।

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति : २५ पैसे। चन्दे की रकम इस पत्र पर भेजी जानी चाहिये अतिरिक्त एकाउण्ट्स ऑफिसर (कैश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इलाहाबाद, बम्बई-९६ (ए एस्)।

इस अंक के लेखक

वंकुण्ठ लल्लूभाई मेहता

—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य।

कृष्णन श्रीकण्ठन नायर

—क्वीलन स्थित क्वीलन जिला सहकारी बैंक लि० के आयोजन, अनुसंधान और सांख्यिकी विभाग के मुख्य अधिकारी।

चित्तूरी वेंकट राघवलू

—त्राल्टेयर स्थित आंध्र विश्वविद्यालय के राजनीति-शास्त्र विभाग में लेक्चरर।

यशवन्तसिंह डी. जाडेजा

—जूनागढ़ स्थित भारत सरकार के 'रूरल सोशलॉजी, ओरियंटेशन एण्ड स्टडी सेण्टर' में शिक्षक।

जागेश्वर गोपाल श्रीखण्डे

—वर्धा स्थित खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला के भूतपूर्व निर्देशक।

यशवन्त विठ्ठल खेर

—वर्धा स्थित खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला के भूतपूर्व जूनियर साइटिफिक ऑफिसर।

तण्डलम सोमसुन्दर यशवत

—मद्रास स्थित मद्रास विश्वविद्यालय के कृषिक अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र में प्रवर अनुसंधान कर्ता।

रामकृष्णन राजगोपालन

—मद्रास स्थित मद्रास विश्वविद्यालय के कृषिक अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र में सांख्यिकीय सहायक।

त्यमगुण्डलू कृष्णभूति

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के मद्रास स्थित ग्रामीण तेल उद्योग विकास अधिकारी।

खेमराज पिछोलिया

—वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) स्थित कृषिक अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र में प्रवर अनुसंधान सहायक।

गुलजार सिंह

—हिमाचल प्रदेश के बनजार (कुठू) में विस्तार अधिकारी (पशु-पालन)।

इन्दर मोहन लाल भटनागर

—लेखक और पत्रकार।

सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर

गन जनवरी माह में भुवनेश्वर में कांग्रेस का ६८वां अधिवेशन हुआ था और उस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'लोकतन्त्र और समाजवाद' नामक प्रस्ताव स्वीकृत किया। उक्त प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस ने श्री उ न देबर की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया, जिसे देबर कमेटी के नाम से जाना जाना है। इस उप-समिति ने अपने प्रतिवेदन में आम जनता की हालत सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता प्रकट की है। प्रतिवेदन में कमेटी ने कृषि और पशु-पालन के विकास, औद्योगिक विकास की पद्धति के नियमन और राष्ट्रीय प्राथमिकता तथा सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप ऋण और विनियोजन योग्य साधन जुटाने के लिए प्रभावी और सत्वर उपाय काम में लाने की आवश्यकता प्रकट करते हुए लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाने की जरूरत पर विशेष प्रकाश डाला है। उप-समिति का प्रतिवेदन कुछ अशो को छोड़ कर यहां पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। श्री उ न. देबर, श्री सी सुब्रह्मण्यन, श्री सादिक अली, श्री श्याम नन्दन मिश्र और श्री बलिराम भगत उप-समिति के सदस्य थे।

राष्ट्र ने जिस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को यथा सम्भव शीघ्रतापूर्वक स्थापित करने का सकल्प किया है उसकी सारभूत विशेषताओं की रूपरेखा भुवनेश्वर में स्वीकृत 'लोकतन्त्र और समाजवाद' नामक प्रस्ताव में दी गयी है। प्रस्ताव में विशेषतः निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है

क देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुष और बालक की आहार, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति,

ख उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के साधन रूप में, और साथ ही क्योंकि सामाजिक न्याय की भावना एक विकास-शील लोकतन्त्र में निहित होनी चाहिये इसलिए, सामाजिक स्तरों में मौजूद बड़ी विषमताओं को कम किया जाय,

ग लोगों के सोचने-समझने और रहने-सहने के ढंग में लोकतन्त्रवादी तरीकों से आवश्यक मूल परिवर्तन किए जायें ताकि मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सुगमतापूर्वक हो सके, जिसके आधार पर ही केवल उस विशाल मानव-साधन का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सकेगा जिससे देश सम्पन्न है, और

घ पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक इन उद्देश्यों

की पर्याप्त परिमाण में पूर्ति का सकल्प राष्ट्र को अपने सम्मुख रखना चाहिये।

व्यूह-रचना

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो मूल व्यूह-रचना अथवा नीति अपनायी गयी है उसकी रूपरेखा पंच वर्षीय योजनाओं में दी गयी है। यद्यपि यह मानना होगा कि यह एक कठिन व्यूह-रचना है और भविष्य निर्माण के लिए वर्तमान में जनता से कड़ी साधना तथा बलिदान की मांग करती है, फिर भी यह महसूस किया जाना जरूरी है कि स्वाधीनता कायम रखने तथा मानवीय न्याय के नियमों के अनुकूल समृद्धि का आश्वासन पाने के लिए और कोई आसान रास्ता नहीं है। जबकि हम इस दृष्टिकोण को उचित मानते हैं, इस बात पर जोर देना भी हम जरूरी समझते हैं कि ऐसी हालत में पैदा होनेवाले तनावों और खिंचावों का सगठन और साथ ही प्रशासन को ध्यान रखना चाहिये। इनकी (सगठन और प्रशासन की) नैतिक जिम्मेदारी है कि प्राप्त फलों और जनता के प्रयास के बीच एक उचित सम्बन्ध हो और न केवल आभारों और बलिदानों, बल्कि उनसे प्राप्त फलों का भी समुचित वितरण हो।

यथार्थ रूप में इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय प्रयासों की दिशा नीचे लिखे अनुसार हो

अ. आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में अधिक तेजी से प्रगति, ताकि तीसरी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके और चौथी व बाद की योजनाओं में और भी अधिक बढ़ी हुई गति के लिए राष्ट्र तैयार रह सके, और

आ. आयोजन तथा उसकी पूर्ति का भार उठाने वाले लोगों द्वारा देश की अर्थ-व्यवस्था की नींव सुदृढ़ बनाने और साथ ही उसे व्यापक बनाने की दिशा में प्रयास किया जाय, ताकि हमारे समाज के निम्न और उच्च स्तर के बीच का फर्क कम हो सके। अगर पक्के इरादों के साथ और ज़रूरत के काम किया जाय तो अगले कुछ वर्षों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग सात प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि हो सकेगी। हमारी राय है कि केवल इसी प्रकार उपर लिखित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकना हमारे लिए सम्भव हो सकेगा।

पहली कमियों का कारण

यदि गत कुछ वर्षों के परिणाम देश की आशानुसार नहीं हुए तो यह असफलता ब्यूह-रचना की नहीं बल्कि अधिकतर कार्यान्वयन की है। यह एक बहुत ज़रूरी काम है जिस पर देश, सरकार तथा कॉग्रेस संगठन को देश के विकास के प्रयास के इस क्रम में, विशेष ध्यान देना है।

जन साधारण की भौतिक समृद्धि पर आश्वासन और उसकी पूर्ति के बीच के अन्तर के कारण जितना ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्र में, विशेषतः कृषि में, हुआ है उतना और कहीं नहीं हुआ और न कहीं संगठन की कमजोरियों और अभावों के कारण असफलता इतनी स्पष्ट है जितनी कि इस क्षेत्र में है। आर्थिक कार्यकलाप के अन्य क्षेत्रों में यथा सम्भव प्रगति करते हुए भी यह इन्कार नहीं किया जा सकता कि निकट भविष्य में कृषि क्षेत्र ही जनता को सबसे अधिक रोजगार दिलानेवाला और उपभोग्य वस्तुएँ उपलब्ध करनेवाला क्षेत्र बना रहेगा, और केवल कृषि-उत्पादन का एक पर्याप्त उच्च स्तर प्राप्त करके ही अर्थ-व्यवस्था का विकास अधिक गति में हो सकेगा।

अतः यह कमेटी नितात आवश्यक समझती है कि तत्काल वर्तमान में और साथ ही आगे भी एक अवधि में इस क्षेत्र में प्रगति की जाय और योजना आयोग द्वारा देश तथा सरकार के सम्मुख तीसरी योजना के शेष दो वर्षों में तथा उसके बाद अगले दस वर्षों में प्राप्त किये जा सकने वाले, किन्तु सुनिश्चित, लक्ष्य रखे जायें। कमेटी महसूस करती है कि तीसरी योजना की अवधि में प्रति वर्ष की वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया है, वह आवश्यकता से अधिक आशावादी नहीं है। चौथी और पाँचवी योजनाओं की अवधि में हमारा ध्येय लगातार प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत वृद्धि का होना चाहिये। जो भी हो, कृषि उत्पादन को १९६५-६६ के अन्त तक ९ करोड़ २० लाख से ९ करोड़ ४० लाख टन तक बढ़ाना होगा। इसका अर्थ है कि अगले दो वर्षों में प्रति वर्ष सात से आठ प्रतिशत वृद्धि की जाय। अतः इस क्षेत्र में तेजी के साथ और लगातार वृद्धि के लिए आनेवाली मानवीय असफलताओं को दूर करना तत्काल आवश्यक है।

कृषि में प्रगति करने के उपाय तीसरी पंच वर्षीय योजना में बतलाये गये हैं। किन्तु केवल इन उपायों से तब तक फल नहीं मिलेगा जब तक एक उचित वातावरण और साथ ही एक समुचित संगठन और व्यवस्था कायम नहीं की जाती कि जिनसे उत्पादन बढ़ाने के इन उपायों का सूक्ष्म प्रयोग हो सके। मुख्यतः इस क्षेत्र के लिए अगले दो वर्षों में किये जानेवाले काम के बारे में हम कुछ विशेष सुझाव देना चाहेंगे। हम एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि आगामी दो वर्षों में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसका बहुत अधिक महत्व है।

भूमि-सुधार

केवल किसान का प्रयास और उत्साह ही ग्रामीण जीवन में क्रांति ला सकता है। यदि आर्थिक और सामाजिक अवस्था ऐसी बनी रही कि ज़िम्मे किसान सुरक्षा तथा अपने श्रम के फल के पूर्ण उपभोग से वंचित रहे तो उससे इस क्षेत्र में भरसक प्रयत्न करने की आशा

करना युक्तिसंगत नहीं होगा। किसान को इस आवासन का दिलाना सरकार और कांग्रेस संगठन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिये।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्व प्रथम आवश्यक है कि भूमि-सुधार कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वित किया जाय। अगले दो वर्षों में भू-अधिकारों के पुनर्वितरण के उपायों, साथ ही मध्यस्थों के उन्मूलन, भू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा लागू किये जाने, भू-धारण अधिकार की सुरक्षा के आश्वासन, लगाने की दरों का निर्धारण तथा उचित मालगुजारी ठहराने और अधिकारों के रिकार्ड की तैयारी आदि उपायों की कार्यक्षम पूर्ति के लिए सुदृढ़ प्रयास किये जाने चाहिये। पट्टेदारों द्वारा मुआवजे की अशायगी पर उन्हें भू-धारण अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

देश में यह एक आम भावना है कि कानूनी उपायों से जो आश्वासन मिले है उन्हें देखते हुए छोटे काश्तकारों, पट्टेदारों और कृषि कर्म करनेवाले श्रमिकों को मिलने-वाला वास्तविक लाभ अपर्याप्त है। भूमि सुधार कार्यक्रम को पूरा करने की तारीखें हम कई बार तय कर चुके हैं, किन्तु व्यावहारिक रूप में उनका पालन नहीं हुआ। अब निश्चित रूप से वचनबद्ध होना जरूरी है ताकि और अधिक निराशा की गुंजाइश न रहे।

भूमि सुधारों की पूर्ति से ग्राम अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन का एक अध्याय समाप्त हो जायगा। इस प्रकार हम ग्राम अर्थ-व्यवस्था को एक सुदृढ़ और सुस्थिर आधार प्रदान कर सकेंगे, क्योंकि तब किसानों को अपने श्रम और अपनी पूँजी का फल मिलने का विश्वास होगा।

कृषि विकास की जिम्मेदारी

साथ ही साथ अगले दो वर्षों में हमें ९ करोड़ २० लाख टन से ९ करोड़ ४० लाख टन तक खाद्योत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति का पूरा आश्वासन होना चाहिये। इस ध्येय को दृष्टि में रखते हुए कमेटी की राय है कि देश में पेंकेज प्रोग्राम क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये।

इस समय देश में लगभग २५० सघन कृषि विकास क्षेत्र हैं, जिनमें साधन-सामग्री सम्बन्धी उचित सुविधाएँ उपलब्ध की जा चुकी हैं। इनके लिए सविस्तार कार्यक्रम बनाये गये हैं। ये क्षेत्र सम्बन्धित राज्यों की सलाह से चुने गये हैं और इनके उत्पादन लक्ष्य भी उन्हीं की सलाह से तय किये गये हैं। अतः कोई कारण नहीं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी प्रकार की असफलता रहे, जब तक वर्षा ही बिल्कुल न हो।

इसी प्रकार सघन कृषि विकास क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रशासन को योजना आयोग और भारत सरकार की सलाह से तीसरी पंच वर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए निर्धारित किये जानेवाले कार्यों को पूरा करना चाहिये।

अभी तक कृषि सुधारों और कृषि विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति असंतोषजनक रही है, जिसका प्राथमिक कारण सुनिश्चित कार्यों की पूर्ति के लिए निर्यात सौंपने में अस्पष्टता रही है। प्रशासनीय पक्ष की इस कमजोरी को दूर करने के लिए मजबूत कदम उठाये जाने बहुत जरूरी है। अतः हमारा सुझाव है कि अगले वर्षों में लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता रहने पर मुख्य मन्त्री तथा कार्य-भार सम्भालनेवाले मन्त्री को कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये, और यदि कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड किये गये काम से सन्तुष्ट नहीं है तो जिम्मेदारी निभाने की असमर्थता का परिणाम जो होता है, होना चाहिये।

मुख्य मन्त्री और योजना के लक्ष्य की पूर्ति का भार वहन करनेवाले मन्त्री के उत्तरदायित्व की यह धारणा अब से हमारे संगठन में मन्त्री-पद की जिम्मेदारी का एक सामान्य अंग समझी जानी चाहिये। पदाधिकार के साथ-साथ आवश्यक योग्यता प्रदर्शित करने का आधार भी होगा, जिसका प्रतबिम्ब फलप्राप्ति से दिखायी देगा। इससे सतर्कता और सजगता पैदा होगी और साथ ही सब स्तरों पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।

तीसरी योजना के अन्त तक पूरे किये जाने के लिए

कृषि से सम्बन्धित नीचे लिखे कुछ अन्य सुझाव दिये जा रहे हैं

१ सारे देश में १९६२-६३ के अन्त तक साधन सहकारी समितियाँ स्थापित करने का हमारा इरादा था। अब इस लक्ष्य को कम से कम तीसरी योजना के अन्त तक पूरा किया जाना चाहिये। जिन इलाकों के पिछड़ेपन के कारण आवश्यक जन-उत्साह पैदा करना कठिन है, वहाँ इस अवधि में सहकारी समितियाँ स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिये। सरकार द्वारा इस दायित्व के समुचित पालन के लिए किसी एक अधिकारी को खास तौर पर जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिये। जब तक सहकारी सगठन का यह ताना-बाना पूरा नहीं हो जाता, समय पर बीजो व ऋण की उपलब्धि तथा साथ ही समय पर कृषि पदार्थों की बिक्री कठिन होगी।

२ अलाभकर आराजियोवाले किसानों की मदद के लिए भी सारे देश में सम्मिलित सेवा कार्यक्रम सगठित करना होगा, ताकि वे अपनी भूमि पर लाभकर खेती कर सकें और सामान्य खर्च पर उन्हें विज्ञान और तकनालाजी का लाभ उपलब्ध हो सके। शुरू में अलाभकर आराजियोवाले किसानों को सम्मिलित सेवा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अन्त में समुचित आकार की लाभकर इकाइयों के आधार पर सम्मिलित आयोजन सम्भव होना चाहिये।

३ तीसरी योजना के अन्त तक हर विकास खण्ड में कम से कम एक केन्द्रीय स्थान में भू-परीक्षण सम्बन्धी साज-सामान उपलब्ध किया जाना चाहिये जिससे वैज्ञानिक कृषि आरम्भ हो सकेगी।

४ अगले दो वर्षों में कृषि औजारों को बनाने और उन्हें उपलब्ध करने का काम भी सगठित किया जाना चाहिये, ताकि चौथी योजना के अन्त तक ऐसा कोई किसान न रहे जिसे बेहतर औजार चाहने पर न मिल सके।

व्यापार और मूल्यों का नियमन

कृषि विकास क्षेत्र में तीसरा प्रमुख कार्य कृषि पदार्थों

के उत्पादकों अर्थात् किसानों को एक लाभप्रद मूल्य का आश्वासन दिलाना है। यह काम जितना पेचीदा है उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि कृषि पदार्थ जन-उपयोग की वस्तुएँ होती हैं और इनके मूल्य में किसी प्रकार की अनुचित वृद्धि से समाज के निर्बल अंगों पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने गत कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं पर अनुचित भार डाले बिना किसान को लाभ पहुँचाने के लिए कई प्रकार की कार्यवाहियों की हैं, किन्तु इनको पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया है, जिसका नतीजा है कि किसानों को मिलनेवाले मूल्यों के स्तर से कहीं अधिक मूल्य उपभोक्ताओं को देना पड़ रहा है।

आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि आवश्यक खाद्यपदार्थों और वस्त्रों का मूल्य समय-समय पर बढ़ता रहा, जैसा कि अभी तक होता रहा है, तो विकास के बोझ का समुचित वितरण नहीं हो सकता। जिस समाज-वादी ढंग की हमने कल्पना की है उसे यदि यथार्थ रूप में परिणित होना है तो, खाद्य-पदार्थों, विशेषतः खाद्यान्नों और वस्त्र जैसी सामान्य उपभोग की अन्य वस्तुओं के मूल्यों के कार्यक्षम नियमन के लिए अगले दो वर्षों में मजबूत कदम उठाने होंगे। इस ध्येय की पूर्ति के लिए सरकार को तीसरी योजना की समाप्ति से पूर्व खाद्यान्नों के व्यापार में अपनी आज्ञा पालन करवाने की स्थिति में होना पड़ेगा। इसके बिना एक ओर किसानों को और दूसरी ओर उपभोक्ताओं के खासतौर पर ज्यादा जरूरत-मन्द भाग को उचित मूल्यों का आश्वासन दिलाना असम्भव होगा। हमारी राय से नीचे लिखे कदम उठाये जाने चाहिये

क सरकार द्वारा न्यूनतम सहायता प्राप्त मूल्यों का निर्धारण और उनकी घोषणा की जानी चाहिये, ताकि किसानों को मुख्य खाद्यान्न के लिए उचित लाभ प्राप्त हो सके। केन्द्र और राज्यों की सरकारों द्वारा इन कीमतों पर असीमित खरीदारी करनेवाली इकाइयों सभी प्रारम्भिक मण्डियों में स्थापित करनी चाहिये। इससे मजबूर होकर सकट वश पैदावार बेचना खत्म करने में मदद मिलेगी।

ख केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित जाँच करने के बाद हर पदार्थ के लिए उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक लाभांश निर्धारित किया जाना चाहिये। यह लाभांश प्रोसेसिंग अथवा अन्य व्ययों के लिए होगा।

ग खाद्यान्न के थोक व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही काम करने की इजाजत मिलनी चाहिये। यह नीति स्वीकार की जा चुकी है और राज्य सरकारों द्वारा इस नीति को कारगर तौर पर अमल में लाया जाना चाहिये।

घ अन्तरिम काल में लाइसेंसशुदा व्यापारियों द्वारा बेचे जानेवाले खाद्यान्नों का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये। इन मूल्यों पर व्यापारियों का सारा गल्ला बेचा जा सकता चाहिये, बशर्त कि इसके लिए सरकारी अनुमति हो।

ङ जब तक कि सरकार उनका संचालन भारस्वयम् नहीं ले लेती, चावल की मिलों को प्राप्त प्रोसेसिंग सुविधाओं पर सरकार की सख्त निगरानी होनी चाहिये ताकि प्रोसेसिंग की कीमतों का नियमन किया जा सके और साथ ही व्यापारिक गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण रखा जा सके। खास तौर पर धान की खेती करनेवाले प्रमुख राज्यों में चावल की मिलों को सरकार के नियन्त्रण में रखना चाहिये और उन्हें सौदेबाजी करने की मनाही होनी चाहिये।

उपभोक्ता सहकारी भण्डार

च राज्य सरकारों और अन्य सरकारी इकाइयों को प्रोसेसिंग और थोक व्यापार की गतिविधियों में अपनी आज्ञा पालन करने की स्थिति में होने के साथ-साथ शीघ्र ही उचित मूल्यों की दूकानों तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की संख्या बढ़ानी चाहिये, जहाँ से उपभोक्ताओं को एक निर्धारित और उचित मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त होगा। सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना और अधिकृत उचित मूल्यों की दूकानों द्वारा समुचित व्यवहार के लिए काँग्रेस सगठन को पहले की अपेक्षा अधिक ठोस जिम्मेदारियाँ अपनानी चाहिये।

छ अनाज की जखीरेबाजी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए, जोकि निजी व्यापारियों द्वारा की जाती है, तथा साथ ही राज्य निदेशालयों अथवा राज्यों के तत्वावधान में संचालित इकाइयों से वितरण के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार तथा कार्यक्षमता के अभाव को दूर करने के लिए काँग्रेस सगठन को अपनी एक व्यवस्था कायम करनी होगी।

ज अगले दो वर्षों में सरकार द्वारा खाद्यान्नों के हर व्यापारी को हिदायत दी जानी चाहिये कि उसे जिस मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त हुए हैं और जिस मूल्य पर वह उन्हें उपभोक्ता को बेचता है, इन दोनों का प्रदर्शन करे। इस प्रकार के ब्यौरे में खरीदे गये खाद्यान्न की मात्रा और बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा का हवाला भी होना चाहिये।

हमें विश्वास है कि यदि दृढ़ सकल्प के साथ और समाज के निर्बल वर्गों की भलाई को ध्यान में रखते हुए इन कदमों को ठीक तरीके से उठाया गया तो जनता में उनका स्वागत होगा और उन्हें जन-सहयोग प्राप्त होगा जिसके परिणाम-स्वरूप कृषि विकास के लिए सुझायी गयी अन्य नीतियों का क्रियान्वयन सक्षम और सुगम रूप से हो सकेगा।

पशु-पालन

हर राज्य सरकार द्वारा कृषि की भौति पशु-पालन, मुर्गी-पालन, मछली-पालन इत्यादि के विकास के लिए भारत सरकार और योजना आयोग की सहायता से अगले दो वर्षों में किये जानेवाले काम तय किये जाने चाहिये। इस देश में पशु-धन के विशाल साधनों के सदुपयोग के लिए अभी तक सुव्यवस्थित प्रयास नहीं किये गये हैं। इस क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि तथा तेजी के साथ उत्पादन की सम्भावना के बारे में भी अभी तक बहुत कम महसूस किया गया है। यदि इस क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाये तो अन्य क्षेत्रों में विनियोग और उत्पादन का जो अनुपात है उससे कहीं ज्यादा इस क्षेत्र में फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा जैसे-जैसे देश का विकास होता है, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र द्वारा

उपलब्ध किये जानेवाले पूरक खाद्य और अन्य कच्चे माल की माँग तेजी से बढ़ती जायेगी। इससे क्षेत्र में उपलब्ध स्वाभाविक साधनों के वैज्ञानिक विकास पर यदि पूरा ध्यान दिया जाय तो एक अल्पतम विनियोग से वैकल्पिक और पौष्टिक आहारों की उपलब्धि शीघ्र ही बढ़ायी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ससे मवेशी पालनेवाली एक बड़ी आबादी को मदद मिलेगी जिसकी सरया लाखों में है और जिनमें से अधिकतर खानाबदोश हैं और जो आज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मृतप्राय हो चले हैं।

इस क्षेत्र में विकास के दो पहलू हैं, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। पहली बात मवेशियों की किस्म में सुधार है, जोकि चुने हुए जानवरों के पालन-पोषण तथा चारे और अन्य प्रकार के आहार के उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों द्वारा किया जाना चाहिये। दूसरी बात पशु-पालन उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए बिक्री की उचित सुविधाएँ उपलब्ध करना है। ये दोनों पहलू परस्पर निर्भर हैं और इनमें सामंजस्य लाना होगा। जब तक सुविधा प्राप्त नहीं होगी, गाँव के लोगों को राष्ट्र के इस धन की वृद्धि करने के लिए उत्साह प्राप्त नहीं होगा। अतः हम इस मामले में एक उचित नीति बनाने और उसे काम में लाने को सबसे अधिक जरूरी समझते हैं।

देश के पशु-पालन में सुधार लाने के लिए, जिसमें दूध देनेवाले पशु सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, हमारा सुझाव है कि अगले दो वर्षों में नीचे लिखे कार्य पूरे किये जायें।

क प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड, पशु-पालन के विकास की सम्भावना का आका जाना,

ख घटिया किस्म के पशुओं के बध्यकरण कार्यक्रम को अमल में लाया जाना,

ग स्वस्थ किस्म के सण्डों की उपलब्धि, और यदि प्रत्येक विकास खण्ड में सम्भव न हो तो कुछ विकास खण्डों के एक समूह में इनके पालन-पोषण की आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धि,

घ ऊसर और कृषि-योग्य बजर जमीन को शीघ्र ही

चरागाहों में बदलना तथा चारे और पशुओं के अन्य प्रकार के आहार को वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त करने की सुविधा,

ङ. बिक्री की मौजूदा सुविधाओं और विकास कार्य को परस्पर सम्बन्धित किया जाना,

च पशु-पालन की नीति स्थिर करना, जिससे वैज्ञानिक विकास सम्भव हो और कम मेहनत तथा साथ ही चारे और अन्य प्रकार के आहार के साधनों का कम व्यय हो,

छ पशु-पालन उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए मूल्य-नीति का निर्धारण और इन धंधों में काम करनेवालों को शोषण से बचाना,

ज ऋण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन, ताकि पशुपालन करनेवालों को ऋण की सुविधाएँ प्राप्त हो सकें, और

झ मृत पशुओं के अवशेषों का वैज्ञानिक आधार पर उपयोग।

जहाँ तक बिक्री का सम्बन्ध है, पशु-पालन उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सग्रह और विक्रय तथा साथ ही कोल्ड स्टोरेज, वस्तुओं को डिब्बों में बन्द करने तथा सुविधाओं के विकास के लिए सरकार की ओर से सहकारी संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिये। परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं में भी वृद्धि करनी होगी। इन पदार्थों के कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के लिए सामान्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि किसान निजी पूँजीवादी संगठनों के शोषण का शिकार न बन सकें। खास तौर पर कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्थापित इकाइयों के विस्तार का एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये और उसे जल्द अमल में लाया जाना चाहिये।

कृषि औद्योगिक विस्तार

ग्रामीण उद्योगीकरण को देश के आर्थिक विकास के आयोजन के एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। जैसा कि डा० धनजय राव गार्डगल ने कहा है कि ग्रामीण उद्योगीकरण

के ध्येय में देश का एक ऐसा उद्योगीकरण निहित है जोकि व्यापक रूप से फैला हुआ और छोटे पैमाने पर होना चाहिये और उसकी आर्थिक सामर्थ्य विकास की प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं तथा सूक्ष्म तकनीकों के अनुरूप होनी चाहिये। इसके अर्थ है, गाँव में उपलब्ध जन-शक्ति तथा कृषि सम्बन्धी और अन्य प्रकार के कच्चे माल के साधनों का समुचित उपयोग और साथ ही गाँवों में प्रोसेसिंग तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों का अधिकतम सोद्देश्य विकास।

जबकि ग्रामीण उद्योगीकरण के कार्यक्रम के विकास में व्यापक विस्तार की कल्पना करना सिद्धातत आसान है, इस कार्यक्रम के विकास को वास्तविक रूप में परिणित करने में कई प्रकार की मूलभूत कठिनाइयाँ सामने आती हैं। ग्रामोद्योग के सिवाय, जो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अधीन है, इस समस्या का हल करने के लिए और कोई सगठन नहीं है। इस प्रकार के काम में रुचि रखनेवाले उद्यमी लोगो की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है। शायद कपास की उपलब्धि के सिवाय, जहाँ कि एक प्रकार का सगठन मौजूद है, कच्चे माल की उपलब्धि के क्षेत्र में सम्पूर्ण अव्यवस्था है। ऋण सम्बन्धी कायदे-कानूनों से विस्तार की राह सुगम नहीं हुई है। विक्रय संस्थाओं का अस्तित्व ही नहीं है। जब तक इन बाधाओं को साथ-साथ दूर नहीं किया जाता, बड़े पैमाने पर विस्तार के प्रयत्नों का सवाल पैदा नहीं होता।

अत्यावश्यक कदम

इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कृषि और पशु-पालन के क्षेत्र की भाँति देश के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम में एक अभिन्न अंग के रूप में ग्रामीण उद्योगीकरण को एक मजबूत आधार पर कायम करने के लिए हम चाहेंगे कि नीचे लिखे कदम पूरी सजीदगी के साथ उठाए जायें

१ हमें यह समझना चाहिये कि उपभोक्ता वस्तु-उद्योगों के क्षेत्र में कम से कम कुछ उद्योगों की पूरी सामर्थ्य का लाभ नहीं उठाया जा रहा है। फिर भी विस्तार हो

रहा है। इस विस्तार का अर्थ है कि सरकार इन नयी इकाइयों को कच्चा माल और अन्य साधन दिलाने के लिए स्वतः वचनबद्ध हो जाती है। इससे सदा के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण का क्षेत्र सीमित हो जाता है। चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो भारी विनियोग किया जाना है, उसे देखते हुए आज की स्थिति और अधिक सकटमय बन जाती है। आज देश की अवस्था को देखते हुए हमें यह समझना चाहिये कि लघु अथवा कुटीर स्तर के विकेन्द्रित उद्योगों का देश की अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। निस्संदेह सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रियाओं में कृषि और पशु-पालन के बाद ग्रामीण उद्योगीकरण का महत्व सबसे अधिक है। हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था के आधार को व्यापक बनाना है तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे बिना रहा नहीं जा सकता। इस मामले में उच्चस्तरीय नीति विषयक निर्णय आवश्यक है।

२ दूसरे, जबकि ग्रामीण उद्योगीकरण की कल्पना वर्तमान तरीकों को जारी रखने के एक सकीर्ण और सीमित अर्थ में नहीं की गयी है, फिर भी हमको यह समझना चाहिये कि यदि ग्रामीण उद्योगीकरण को बड़े पैमाने के सगठित उद्योगों और श्रेष्ठतर तकनीकों का लाभ प्राप्त है, और ये अन्य सुविधाएँ प्राप्त हैं, जोकि सुस्थापित इकाइयों को आम तौर पर प्राप्त होती हैं और जो प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था में सामान्यतः उपलब्ध होती हैं, तो ग्रामीण उद्योगीकरण को अपने आरम्भिक क्रम में सरकार और समाज का यथा सम्भव अधिकतम समर्थन प्राप्त होना चाहिये।

३ यदि पंचम योजना के अन्त तक बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या और रहन-सहन के न्यूनतम स्तर की गारण्टी देने की समस्या को कारगर तौर पर हल करना है तो अगले दो वर्षों में सरकार को एक उचित ढंग का सगठन सुस्थापित करना होगा। हमारी राय है कि इस काम को शुरू करने के लिए एक निकाय तत्काल स्थापित किया जाय। यह भारत सरकार

के उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय होता चाहिये, जोकि ग्रामीण उद्योगीकरण के कार्यक्रम की पूर्ति पर ध्यान देगा। जैसे-जैसे काम बड़े, स्थिति के आवश्यकतानुसार राज्यों में और यहाँ तक कि क्षेत्रों में इस प्रकार के निकाय स्थापित किये जा सकते हैं।

४ गाँवों के उद्योगीकरण के कार्यक्रम को दस्तकारों की सहकारी समितियाँ अथवा उनकी पजीकृत संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिये। दस्तकार ज्यादातर खुद अपना रोजगार पैदा करनेवाले लोग होते हैं और इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि राज्य की सहायता के परिणाम स्वरूप राज्य और दस्तकार के बीच एक शोषक वर्ग पैदा न हो जाय।

५ यदि ग्रामीण उद्योगीकरण के कार्यक्रम की जड़ें अविलम्ब जमाना हैं तो वित्त, बिजली और कच्चे माल के वितरण तथा परिवहन के मामले में उन्हें अपेक्षाकृत उच्च प्राथमिकता देनी होगी। यदि ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को लाभकर बनाना है तो खास तौर पर बिजली सप्लाई की दर पर पुनर्विचार करना होगा। इन सुविधाओं की उपलब्धि के बाद सरकार द्वारा स्थापित सगठन की जिम्मेदारी होगी कि वह कच्चे माल, ऋण, बेहतर औजारों और तकनीकी जानकारों की उपलब्धि के बारे में योजनाएँ बनाये। साथ ही अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य का सगठन तथा औजारों का निर्माण व बेहतर किस्म के औजारों का वितरण भी सरकार द्वारा स्थापित इस सगठन की जिम्मेदारी होनी चाहिये।

नीति मूल्यांकन

उपर्युक्त न ४ और ५ का अर्थ है कि सामाजिक और आर्थिक ऊपरी लागत के मामले में सरकार द्वारा अभी तक अपनायी गयी नीतियों की समीक्षा की जाय।

हम समझते हैं कि इस काम के लिए अगले दो वर्षों में एक निर्भीक और कल्पनाशील प्रयत्न करना आवश्यक है। वैज्ञानिकों की और नयी तकनीकों के प्रादुर्भाव

से कृषि और पशु-पालन के क्षेत्र में उत्पादन की प्रविधियों पर सीधा असर पड़ेगा। गाँवों में प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध बनानेवाली परम्परा के गहन आवरण को भेदना अत्यन्त आवश्यक है। ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में विस्तार से भी भारत की प्रगति को अवरुद्ध बनानेवाली परम्परा के इस आवरण को भेदने की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी और ग्रामवासियों की विशाल संख्या द्वारा उत्पादन की अपनी समस्याओं को एक नये दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता भी उपजेगी। इस प्रकार गाँव में कृषि और उद्योगों की वर्तमान गतिहीन अवस्था भी समाप्त हो जायगी।

औद्योगिक विकास

कृषि, पशु-पालन और देहात के उद्योगों को प्रधानता देने से जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने, सतत विकास और आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्रुत गति से औद्योगीकरण की आवश्यकता कम नहीं होती। ऐसी स्थिति में, जबकि देश को विदेशी आक्रमण के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, विकास नीति का यह पहलू और भी ज्यादा महत्व रखता है। कुछ लोगों की यह गलत धारणा बन गयी है कि मूल उद्योगों के विकास पर अधिक बल देने से कृषि-विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उपभोग स्तर में सुधार लाने के उद्देश्यों को पूरा करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। असलियत यह है कि अर्थ-व्यवस्था के इन दोनों प्रमुख क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई विरोध अथवा प्रतिस्पर्धा नहीं है। दरअसल कृषि क्षेत्र को उर्वरक, उन्नत ढग के औजार, सिमेंट, लोहा और इस्पात, विद्युत शक्ति, पम्प, मोटर इत्यादि वस्तुएँ औद्योगिक क्षेत्र से ही प्राप्त होती हैं। इन चीजों के बिना कृषि क्षेत्र में उत्पादकता जितनी देश को जरूरत है उतनी नहीं बढ़ायी जा सकती। इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र के बाहर रोजगार के अवसरों में वृद्धि लाने और साथ ही पदार्थों और कच्चे माल दोनों का बजार प्रशस्त करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार बहुत जरूरी है। राष्ट्र की विकास-नीति में कृषि और उद्योग

के परस्पर सम्बन्धों को स्पष्ट रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तो आर्थिक कल्याण तथा सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना आवश्यकता से अधिक कठिन हो जायगा।

इसलिए औद्योगिक विकास का कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिये कि अगले दस वर्षों के भीतर देश ऐसी अवस्था में हो जिसमें विदेशी सहायता पर कम से कम निर्भर रह कर विकास और पूँजी-विनियोग की दर ऊँची बनी रहे। इसके लिए आगामी वर्षों में औद्योगिक उत्पादन के ढाँचे को द्रुत गति से बदलना होगा। विशेषतया, कृषि-विकास के लिए आवश्यक औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन को तेजी से बढ़ाना जरूरी होगा तथा आयात पर कम निर्भर रहने के लिए तेल, धातुओं और मशीनों का उत्पादन बढ़ाना होगा। इन उद्योगों की एक बार सुदृढ़ स्थिति हो जाने पर कृषि और औद्योगिक कच्चे माल को प्रोसेस करने के अनेक उद्योगों के सतत विकास के लिए बुनियाद मजबूत हो जायगी। इनमें से अनेक उद्योग आर्थिक शक्ति और कार्यकलापों के विकेंद्रीकरण के जबरदस्त साधन होंगे। इन बातों को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगले कई वर्षों तक अर्थ-व्यवस्था में हर वर्ष लगायी जानेवाली पूँजी का बहुत बड़ा हिस्सा अर्द्ध-तैयार माल और पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना में लगाया जाना चाहिये, और समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के पूँजी-विनियोग सम्बन्धी प्रमुख निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किये जाने चाहिये।

सार्वजनिक और निजी विभाग

औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में इस प्रकार बाँटी जानी चाहिये कि समाजवाद के उद्देश्य के अनुरूप उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का अनुपात बढ़ता रहे। सरकार के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इन दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत उद्योगों को जिस प्रकार बाँटा गया है, वह इस सन्दर्भ में भी पूर्णतया ठीक है। भविष्य में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत मशीन-

निर्माण उद्योगों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इन उद्योगों के लिए जो लक्ष्य रखे जाये उनकी पूर्ति आर्थिक विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत मशीन निर्माण उद्योगों के कार्यक्षम स्वरूप से इनकी बनायी मशीनों को लगानेवाले अथवा उद्योगों के नियमन में भी सुविधा होगी।

आर्थिक विकास और उत्पादन-साधनों पर सामाजिक नियंत्रण रखने के लिए सरकारी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार अनिवार्य है, इसलिए प्रमुख अर्द्ध-तैयार माल और पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना और उन्हें कार्यक्षमता के साथ चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करना भी सरकार के लिए जरूरी हो जाता है। औद्योगिक नीति-प्रस्ताव पर अमल करते समय लक्ष्यों की क्रमागत पूर्ति, सरकारी और निजी क्षेत्रों के कार्यों में थोड़ी-बहुत हेर-फेर करना जिससे उत्पादन-लक्ष्यों को पूरा करने में देरी न हो, इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। पिछले वर्षों में सरकार ने इस आधार पर तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति को दृष्टि में रख कर सरकारी क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट उद्योगों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश करने की अनुमति दी है। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि निजी क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट उद्योगों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में निजी क्षेत्र के विफल रहने पर सरकार को निजी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त जन-साधारण के उपयोग की कुछ वस्तुओं, जैसे कपड़े का उद्योग, में अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का उपयोग सहकारी अथवा राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत विकेंद्रीकरण के आधार पर होना चाहिये। इन इकाइयों में उत्पादन जन-साधारण के उपभोग की कुछ वस्तुओं तक सीमित रहना चाहिये। वर्तमान इकाइयों को निर्यात के लिए आर्थिक मदद दी जानी चाहिये।

जन साधारण के लिए उत्पादन

उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों के क्षेत्र में हमको अपने

विचारों ने नटना लाना बहुत जरूरी है। इन उद्योगों में उत्पादन सामान्यजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर होना चाहिये। लेकिन हमें डर है कि इन उद्योगों की उत्पादन योजना में उच्च आय वर्ग की आवश्यकताओं का अधिक ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए झूठी चमक-दमक थी वस्तुओं की किस्मों और अत्यधिक उत्पादन पर कठोर नियंत्रण रखना और जन-साधारण के उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर बल देना जरूरी है। इससे उत्पादन-लागत कम होगी और राष्ट्र के सीमित साधन अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाये जा सकेंगे। हम समझते हैं कि इस चीज को औद्योगिक नीति का एक अंग स्वीकार कर लेना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र द्वारा अनेक उद्योगों में उत्तरोत्तर अधिक जिम्मेदारी ले लेने से सरकारी क्षेत्र में समुचित सगठनात्मक परिवर्तन लाये बिना योजना के क्रियान्वयन में देरी होना तथा तकनीकी और प्रबन्ध-सम्बन्धी, परामर्श-खर्च या लागत बढ़ जाना सम्भव है। ऐसे उद्योगों में, जिनमें भारी पूंजी-विनियोग हुआ हो और प्रतिफल प्राप्त होने की लम्बी अवधि हो, यह खर्च विशेषतया ज्यादा होता है। इन खर्चों को कम करने के लिए इस्पात, उर्वरक और रासायनिक पदार्थों के प्रमुख उद्योगों के लिए सरकार को विशिष्ट आयोजन और डिजाइन-सगठन तुरन्त स्थापित करने चाहिये। इस प्रकार के सगठन केवल उनको सौंपे गये मामलों में विशेषज्ञ-मत और सलाह देने के ही योग्य नहीं होने चाहिये, बल्कि वे उनको सौंपे गये उद्योगों के पूर्ण आयोजन के लिए भी जिम्मेदार होने चाहिये। इन सगठनों का उपयोग निजी सगठन के अन्तर्गत विकास के लिए सम्बद्ध परियोजनाओं के औचित्य पर विचार करने के लिए भी किया जाना चाहिये।

निजी क्षेत्र पर नियंत्रण

सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति सरकारी औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ निजी क्षेत्र के विस्तार के ढंग और गति पर प्रभावकारी नियंत्रण रहे बिना नहीं हो सकती। निजी क्षेत्र के सुपुर्द की गयी प्राथमिकता प्राप्त

उद्योगों की परियोजनाओं का वास्तव में क्रियान्वयन हो, इस दिशा में कदम उठाने होंगे। इसमें कोई सदेह नहीं कि इस उद्देश्य के लिए लायसेंस पद्धति जारी रहेगी, लेकिन यदि लायसेंस विधि को आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिए और समुचित सफलता प्राप्त करने के लिए वास्तव में कारगर बनाना है तो लायसेंस देने की विधि में संशोधन किए जाने चाहिये। वर्तमान बड़े औद्योगिक संस्थानों को अपनी परियोजनाओं के लिए लायसेंस, तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होने पर ही दिये जायें। लायसेंस देते समय लायसेंस लेनेवाले द्वारा उठाये जानेवाले कदमों और समय आदि का स्पष्ट चित्र सामने होना चाहिये। सरकार द्वारा आवश्यक सहायता दिये जाने के बावजूद परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देर हुई हो तो सरकार को लायसेंस रद्द कर देना चाहिये और उस परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ले लेना चाहिये। आरम्भ में हमने जिन तकनीकी और प्रबन्ध सम्बन्धी सगठनों का उल्लेख किया है उनकी स्थापना होने पर ही लायसेंस रद्द करने की नीति काम करेगी। लायसेंस रद्द कर देने के माने प्रमुख परियोजनाओं का उन्मूलन नहीं, बल्कि सरकारी क्षेत्र द्वारा उनका प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना है।

लायसेंस विधि को कड़ा बनाना

लायसेंस विधि को कड़ा बनाने के साथ-साथ इकाइयों के स्थान के चयन और इकाई के आकार पर अधिक बल दिया जाना चाहिये, जिससे इकाइयों आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो और उत्पादन लागत उत्तरोत्तर कम हो सके। इस सिलसिले में लाभप्रद आकार की इकाइयों को लायसेंस देने की नीति अपनाने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि उद्योग चलाने की योग्यता अथवा रुपये-पैसे के साधनों की कमी को आधार बना कर कहीं बड़े-बड़े उद्योग-संस्थानों को ही ये लायसेंस न मिलने लगे। बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों की नयी परियोजनाओं के लिए इस प्रकार के लायसेंस

जारी न करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना आवश्यक होगा। अपेक्षाकृत छोटे व्यापार सस्थानों को इस क्षेत्र में आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और सरकार के तत्वावधान में स्थापित की गयी तकनीकी विशेषज्ञों की सस्थाओं और विशिष्ट वित्तीय सस्थाओं को इस प्रकार की व्यापारिक इकाइयों को तरजीह देने की हिदायत दी जानी चाहिये। विशेषतया निजी क्षेत्र के तकनीकी और प्रबन्ध कर्मचारियों को आगे आने के लिए और स्वतः उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिये। इससे आर्थिक शक्ति के जमाव की समस्या हल नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़े उद्योग सस्थानों को और भी ज्यादा बड़ा होने से रोकने के लिए यह एक जरूरी कदम है। निजी क्षेत्र के कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण को वास्तव में रोकने के लिए सरकार को वित्तीय और वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमलापों में अधिक हस्तक्षेप करना आवश्यक होगा।

लायसेंस विधि को उपर्युक्त प्रकार से सख्त बनाने के कारण इस विधि के अनुसार काम करनेवाले प्रशासनिक यंत्र पर भी निश्चय ही ज्यादा दबाव पड़ेगा। इसलिए जब तक औद्योगिक विकास नीतियों पर अमल करनेवाली एजेंसियों पर पड़ रहे दबाव को कम करने की दिशा में कदम नहीं उठाये जाते तब तक भ्रष्टाचार का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जायगा। सामान्यतया इस प्रकार के कंट्रोल के लिए उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अथवा उपयोग निर्दिष्ट करने चाहिये और तदनुसार काम करने अथवा लायसेंस या कोटा देने की नीति अपनायी जानी चाहिये। इस प्रकार के प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की आवश्यकता पूरी होने पर निजी क्षेत्र के अन्य उद्योगों को अपनी आवश्यकताएँ बची हुई सप्लाई से बोली लगा कर पूरी करने की छूट होनी चाहिये। इससे एक ओर तो काला बाजार की सम्भावना कम होगी और दूसरी ओर समुचित वित्तीय उपायों द्वारा सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इस प्रकार की व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि

उपभोक्ताओं को बाध्य होकर अब जो कीमत मुनाफाखोरो को देनी पडती है, उससे अधिक कीमत देनी होगी।

आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था में देश के औद्योगीकरण के लिए हमें आवश्यक रूप में विदेशों से सहायता लेनी होगी। विदेशी सहायता सरकार द्वारा ऋण के रूप में, निजी उद्योगों को ऋण दिलाने और उद्योगों की समाधिकारी पूँजी में हिस्सा लेने के रूप में प्राप्त की जाती है। भारत सरकार ने कुछ छोटे हुए उद्योगों में, जिनमें तकनीकी जानकारी का अभाव है और बड़े परिमाण में पूँजी की आवश्यकता है, विदेशी पूँजी का समाधिकारी हिस्सा-पूँजी में हिस्सा लेने का स्वागत किया है। समाधिकारी हिस्सा-पूँजी में जो विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो, उसका उपयोग सावधानी के साथ ऐसे उद्योगों में किया जाना चाहिये जिनमें हम अपने प्रयत्नों से आगे नहीं बढ़ सकते। हमको विदेशी पूँजी कुछ चुने हुए उद्योगों में उपलब्ध करने और विभेदात्मक ढंग से विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन देने की नीति पर कायम रहना चाहिये।

ऋण की दिशा

सामाजिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ऋण और विनियोजन-योग्य साधन जुटाने के लिए रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों को आदेश देना चाहिये कि वे जो रुपया उधार देते हैं उसका उपयोग उद्देश्य के अनुरूप होता है या नहीं और उधार लेनेवाले उस धन का उपयोग उधार लेने के उद्देश्य के अनुसार करते हैं या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करे। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक के पास बुराइयों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को अपने अधिकारों को काम में लाकर तथा समुचित नियम बना कर यह देखना होगा कि व्यापारिक बैंक रुपया उधार देने में जो प्राथमिकताएँ देते हैं वे योजना में स्वीकृत सामाजिक अथवा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। दूसरे शब्दों में मूल उद्योगों और छोटे उद्योगों, नये

उद्योगपतियों और कृषि-कार्यों को दूसरो को प्राथमिकता देने से पूर्व वित्तीय सहायता मिलनी चाहिये।

रिजर्व बैंक को मौजूदा अधिकारो के अतिरिक्त यह अधिकार भी होना चाहिये कि वह निरीक्षण के पश्चात् (अ) विशेष आडिट की आज्ञा दे सके, (आ) निरीक्षण के समय अनियमितताएँ प्रकाश में आने पर आडिटर नियुक्त कर सके, और (इ) शेयर-होल्डरो द्वारा नियुक्त किये गये आडिटरो के स्थान पर जहाँ जरूरत समझे नये आडिटर नियुक्त कर सके। अनुसूचित बैंक जिनकी शेयर-पूजी और सुरक्षित धनराशि ५० लाख रुपये या उससे ऊपर है, उनका वार्षिक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को कानून के जरिये सौपी जानी चाहिये।

निम्नलिखित दशाओ में व्यापारिक बैंको के, जिनकी अनुचित और अवाञ्छित कार्रवाइयाँ प्रकाश में आये, डायरेक्टरों को बदलने या नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने या सरकारी क्षेत्र के बैंको या अन्य स्वीकृत अनुसूचित बैंकों में उन्हें मिला देने या बैंक का कार्य संचालन अपनी देख-रेख में कराने का पूरा अधिकार रिजर्व बैंक को होना चाहिये और उसको काम में लाने के लिए उसे सदा तत्पर रखना चाहिये

१ रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये निरीक्षण में या रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त आडिटरो के आडिट में यदि किसी बैंक की भारी अनियमितताएँ प्रकट हो,

२ यदि बैंक का लायसेंस रद्द कर दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो,

३ यदि जमा बीमा योजना के अधीन बैंक का पजीकरण निरस्त कर दिया गया हो,

४ सीमित ऋण नियंत्रण नीति के अनुरूप विभिन्न प्रकार के ऋणों के बारे में दिये गये आदेशों का यदि उल्लंघन हुआ हो,

५ किसी एक प्रकार के व्यापार अथवा उद्योग के लिए किसी एक प्रकार की सिक्युरिटी या प्रतिभू पर दिया गया ऋण कुल ऋण के आधे से यदि अधिक हो,

६ ऐसे सस्थान को दिया गया ऋण, जिसमें बैंक के

डायरेक्टर दिलचस्पी रखते हो, यदि कुल दिये गये ऋण के एक-चौथाई से अधिक हो,

७ यदि बैंक के डायरेक्टर-मंडल में ऐसा व्यक्ति हो जिस पर आय कर, मृत सम्पत्ति-शुल्क, बिक्री कर या सीमा शुल्क या विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना हुआ हो या जो आय-कर, मृत सम्पत्ति-शुल्क, बिक्री कर या सीमा शुल्क न देता हो,

८ यदि बैंक के डायरेक्टर मंडल में एक ही संयुक्त परिवार या मैनेजिंग एजेंट समूह के दो या अधिक व्यक्ति हो,

९ यदि बैंक रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करके विदेशों में व्यापार करता हो,

१० रुपया उधार लेनेवाले से रकम का किस प्रकार उपयोग होगा, यह जाने बिना अथवा यह तस्दीक किये बिना कि उधार लेनेवाला उस रकम का बताये गये उद्देश्य के अनुसार उपयोग कर रहा है, यदि कोई बैंक रुपया उधार देता रहे, और

११ यदि बैंक राष्ट्रीय हित के विरुद्ध किसी भी कार्यकलाप में भाग लेता रहे।

छिपा हुआ धन

वह धन जिसका कोई हिसाब नहीं रखा गया, गैर-जिम्मेदार लोगों के हाथों में कई तरीकों से आता है और असामाजिक तथा समाज-विरोधी कार्यों के लिए उसका कई रूपों में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, आयात लायसेंस की बिक्री या हस्तान्तरण आदि, आम बीमा व्यापार में कटौती, अचल सम्पत्ति की बिक्री-खरीद और उसे किराये पर चढाना—खास तौर पर बड़े शहरों में—तस्करी और आयात-निर्यात की वस्तुओं का मूल्य बढ़ा कर धा घटा कर दिखाना, आदि मामले हैं।

इस धन के बारे में जिसका हिसाब नहीं रखा गया है, हमें दो पहलुओं पर विचार करना होगा—(१) समाज में मौजूद इस प्रकार के धन से किस तरह पेश आया जाये, और (२) भविष्य में इस प्रकार के धन के जमा होने को किस प्रकार रोका जाये।

जहाँ तक पहली बात का सम्बन्ध है, आज समाज में इस प्रकार के छिपाये हुए धन की मौजूदगी के खतरे पर जोर देने के लिए किसी तरह की दलीलो की जरूरत नहीं। इस मामले में जितनी सख्त कार्यवाही की जाये, कम है। अतः इस समस्या के बारे में पूरी गम्भीरता के साथ विचार करना होगा। इस प्रकार के धन के एकत्र होने को भविष्य में रोकने के लिए हमें देखना होगा कि किन परिस्थितियों में वह धन पैदा होता है जिसका हिसाब नहीं रखा जाता। इस प्रकार के धन के सग्रह और समाज-विरोधी प्रयोग को मुद्रास्फीति से प्रभावित अर्थ-व्यवस्था में प्रोत्साहन मिलता है। मूल्यों में जितनी स्थिरता होगी, उतनी ही इस प्रकार के धन को जमा करने की गुंजाइश कम होगी। सरकारी नियंत्रण व्यवस्था, आम बीमा क्षेत्र और शहरो में सम्पत्ति के हस्तांतरण सम्बन्धी मामलो से भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश सहायक सिद्ध होगी। गैर-बैंकिंग-जरियो से बहुत अधिक धन के लेन-देन और प्रयोग पर रिजर्व बैंक द्वारा ज्यादा निगरानी और नियंत्रण रखा जाना चाहिये। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करो को लगाने और उनकी वसूली की व्यवस्था की लगातार छानबीन की जानी चाहिये ताकि देखा जा सके कि किस प्रकार इनमें सुधार किया जा सकता है और इन्हें कैसे और ज्यादा कारगर बनाया जा सकता है।

यदि इस मौजूदा बेहिसाब धन को समूल नष्ट करने के लिए कदम उठाने के साथ-साथ भविष्य में इस प्रकार के धन सग्रह को रोकने के लिए कदम नहीं उठाये गये तो हर बार हमें सख्त कार्यवाही करनी होगी जिससे समूची अर्थ-व्यवस्था में विघ्न पैदा होगा। अतः इस समस्या के सभी पहलुओं पर समग्र रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

आय की विषमताएँ

अभी तक हम इस समस्या को सब स्तरों पर, खास तौर पर निम्न स्तरों पर आय की वृद्धि के दृष्टिकोण से देखते आये हैं, किन्तु गत दस वर्षों का अनुभव है कि विकास की गति में वृद्धि के साथ-साथ कई नये प्रकार की विषमताएँ पैदा हुई हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को रोकना होगा। तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आय के

उच्चतम और निम्नतम स्तरों के बीच के अन्तर को १ : ३० के अनुपात में क्रमशः घटाने का ध्येय स्वीकार किया गया है जिसे कि आगामी दो या तीन योजना-वर्षियों में पूरा किया जाना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए अधिक सोद्देश्य वित्तीय उपाय काम में लाये जाने चाहिये। जो भी हो, विशेष योग्यता, जिम्मेदारी रखनेवाले तथा जोखिम उठा कर काम करनेवाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। अनर्जित आय और ग्रामीण तथा गैर-ग्रामीण आय के बीच की विषमता की समस्या पर भी विचार करना होगा।

श्रम-नीति

उत्पादन के मामले में मजदूर का पूँजी से कम महत्व नहीं है। आर्थिक विकास का एक उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए सोच-विचार कर श्रम-नीति अपनाना और उत्साही ढंग से उसे अमल में लाना जरूरी है। उन्नत उत्पादन तथा उत्पादनशीलता तभी सम्भव है जबकि श्रमिक आर्थिक विकास की समस्या में दिलचस्पी लेने लगे। समाजवादी समाज में यह काम उद्योगों के संचालन से श्रमिकों को अधिकाधिक सम्बन्धित करके पूरा हो सकता है। वर्तमान अगान्तिपूर्ण श्रम सम्बन्धों को, खास तौर पर सरकारी क्षेत्र की मुख्य औद्योगिक इकाइयों में ऐसे सम्बन्धों को, ध्यान में रखते हुए इन ध्येयों को सामने रखना होगा। भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के मजदूर सघों ने राजनीतिक सघर्षों और आपसी झगड़ों के अन्तर्गत अन्य मजदूर सघीय वैमनस्यों को कारखानों में, ला खड़ा किया है। परिणाम स्वरूप सबसे पहले अनुशासन की हत्या हुई है जिससे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन की क्षति हुई है। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मजदूर सघों के हर राजनीतिक गुट ने एक दूसरे को परास्त करना चाहा है और गुट द्वारा अधिकाधिक अनुचित भागे पेश की जा रही है। मजदूर सघों के बीच ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक सघर्षों से कई जगह झगड़े पैदा हुए हैं। यदि औद्योगिक प्रगति को सुरक्षित और सुनिश्चित बनाना है तो मजदूर सघों की समस्या के प्रति राजनीतिक दलों के रवैये में एक आमूल परिवर्तन आवश्यक है।

देश के सभी राजनीतिक दल अपने साथ मजदूर सघों को सलन रखने के विचार के लिए जिम्मेदार हैं। अब जरूरी है कि मजदूर सघों और राजनीतिक दलों के बीच ऐसे सम्बन्ध के भविष्य पर हम निर्णय करें जिसका कि आर्थिक विकास के लिए बुरा परिणाम होता है। देश को श्रमिकों के लिए एक नयी नीति अपनानी होगी, ताकि श्रमिक अनुशासन पालन करते हुए और साथ ही मजदूर सघ कायम करने की स्वतंत्रता से वंचित हुए बिना काम कर सकें। इस सम्बन्ध में हर औद्योगिक इकाई में गुप्त मतदान द्वारा श्रमिकों के उन प्रतिनिधियों के चुनाव के विचार पर गौर किया जा सकता है, जिन्हें कि कारखानों के मजदूरों की ओर से बातचीत करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का एकमात्र अधिकार होगा। इससे हमारे कारखानों में अनुशासन कायम करने और साथ ही उचित और उत्तरदायी प्रतिनिधित्व प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी। इस तरीके को अपनाने से कारखानों के कार्य-संचालन में श्रमिकों को अधिकाधिक सम्बन्धित करने में भी सहायता मिलेगी।

इस समस्या पर तुरन्त ध्यान दिया जाना जरूरी है और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये तौर-तरीके ढूँढ़े जाने चाहिये, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों के संचालन से श्रमिक वर्ग अधिकाधिक सम्बन्धित हो सके।

न्यूनतम आवश्यकताएँ और सामाजिक सुरक्षा

कमेटी ने अभी तक पिछले पैराग्राफों में भुवनेश्वर में स्वीकृत प्रस्ताव में दिये गये वचन को शीघ्र पूरा करने के लिए बुनियादी विकास कार्यक्रमों की चर्चा की है। अब कमेटी न्यूनतम आवश्यकताओं और सामाजिक सुरक्षा के कुछ पहलुओं के बारे में भी अधिक निश्चित रूप से कुछ कहना चाहती है। इन न्यूनतम आवश्यकताओं का अपना विशेष महत्व है और इनका उल्लेख विशेषतः आवश्यक है।

हमारा सुझाव है कि देश के लोगों को शहरों, कस्बों व गाँवों में वर्ष भर सभी मौसमों में पेय जल उपलब्ध करने के लिए एक क्रमिक योजना बनायी जानी चाहिये। पेय जल की आवश्यक उपलब्धि और साथ ही वर्ष भर सभी मौसमों में उसकी पूर्ति की आवश्यकता पर बल दिया

जाना जरूरी है, क्योंकि अक्सर यह महसूस नहीं किया जाता कि गर्मियों में तथा बारिश न होने पर जल उपलब्धि के प्रबन्ध बहुधा बेकार हो जाते हैं। अतः जल उपलब्धि का पूरा आश्वासन होना चाहिये।

जल-पूर्ति के साधन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध किये जाने चाहिये। इस पुण्य कार्य के लिए जनता से चन्दा इकट्ठा करना भी सम्भव हो सकता है। जिस के रूप में और मजदूरों के रूप में जन सहयोग पाना भी सम्भव है। जल की समस्या हल करनेवाली कई सस्थाएँ हैं। उदाहरण के लिए सिचाई विभाग की कृषि कार्यों के लिए जल पूर्ति की अपनी योजनाएँ हैं। बिजली बोर्डों की भी जल विद्युत योजनाएँ हैं। यहाँ तक कि खनिज विभागों और खनिज उद्योगों को भी अतिरिक्त जल की समस्या का सामना करना पड़ता है। तेल तथा गैस परियोजनाओं के आरम्भिक क्रम में अतिरिक्त जल के निपटाने का प्रश्न कई बार एक समस्या का रूप ले लेता है। एक बार भारत सरकार के सम्मुख जल बोर्ड कायम करने का सुझाव आया था। हमारा खयाल है कि यह सुझाव अच्छा था और इस पर फिर विचार किया जाना चाहिये। केन्द्र और राज्यों में समन्वय तथा कार्य-पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त एक व्यवस्था कायम की जानी चाहिये। हमारा यह भी विचार है कि कृषि विकास के लक्ष्यों की पूर्ति की भाँति इस क्रमिक योजना की पूर्ति को भी उच्चतम महत्व दिया जाना चाहिये और मुख्य मन्त्री तथा कार्य-भार सम्भालनेवाले मन्त्री को असफलता होने पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये।

यह समझना बहुत जरूरी है कि जल-प्राप्ति की समस्या इतनी आसान नहीं जितनी नजर आती है। अभी तक कई बड़े शहरों—जोकि हर माने में आधुनिक हैं, जैसे कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि—के बाहर के इलाकों में जल-प्राप्ति की उचित सुविधाएँ नहीं हैं। इस कार्यक्रम के लिए भारी विनियोग आवश्यक होगा। पाइप लाइनों के जरिये पानी पहुँचाने के लिए एक बड़ी मात्रा में लोहा, इस्पात, और सीमेन्ट की जरूरत होगी। कई स्थानों में बिजली

की मदद से पानी को उच्चतर स्तरों पर पहुँचाना पड़ेगा। अतः क्रमिक योजना में इन सब बातों पर उचित ध्यान रखा जाना चाहिये। निस्सन्देह इस कार्यक्रम की पूर्ति में कुछ समय लगेगा, किन्तु इसे सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए हमारी सच्ची कोशिशों से जनता को भरोसा होगा कि यह एक थोथा वादा नहीं है।

आवास तथा आवास भूमि

यह एक कठिन समस्या है। गाँव और शहर दोनों में बहुत घनी आबादी है। गाँवों में भी यह कठिनाई मौजूद है। गैर-कृषि भूमि की कमी नहीं है, लेकिन गाँव की बढ़ती हुई आबादी के लिए गाँव के निकट ही मकानों की जगह होनी चाहिये और गैर-कृषि भूमि गाँव से दूर होती है। गाँव के निकट कृषि भूमि बहुत मँहगी होती है। ऐसे मामलों में नये गाँव स्थापित करने का सवाल भी पैदा होता है। शहरों में नयी आबादी आने के कारण मकानों के किराये और जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं। मकान मालिकों और साथ ही किरायेदारों के दुर्व्यवहारों से सब प्रकार के झगड़े पैदा होते हैं। इसके अलावा मकान बनाने की सामग्री प्राप्त करना कठिन है। इमारती लकड़ी का भाव अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि घरेलू आधार पर बनायी जानेवाली ईंटों और चूने के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं।

हमारा खयाल है कि निम्न आय वर्गों तथा समाज के निर्बल वर्गों की आवास सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित सुविधाएँ उपलब्ध करने में सरकार और स्थानीय निकायों के दृष्टिकोण में समाजवाद की भावना प्रकट होनी चाहिये। इस काम के लिए नीचे लिखे कदम तत्काल उठाये जाने चाहिये

१. बेघरवार परिवारों की सख्या जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाय। चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत में पूर्व इन परिवारों को मकान के लिए जमीन दिलाने की एक क्रमिक योजना एक वर्ष के भीतर तैयार की जाय। इस काम के लिए सामुदायिक विकास खण्डों का उपयोग किया जाना चाहिये।

२. जीवन बीमा की योजनाओं को स्वास्थ्य-सेवाओं और आवास कार्यक्रम के साथ सबन्धित किया जाय। अगर यह मान लिया जाय कि जीवन बीमा निगम को प्राप्त धन का अधिकांश भाग स्वास्थ्य और आवास के लिए काम में लाया जायेगा तो जनता अनिवार्य जीवन बीमा का विरोध नहीं करेगी।

३. जरूरतमंद लोगों को जमीन और इमारती सामान दिलाने की एक क्रमिक योजना बनायी जानी चाहिये। दो कमरे से कम जगह में रहनेवाले परिवारों को इस योजना से लाभ पहुँचना चाहिये बशर्ते कि वे परिवारनिम्न आय वर्ग में आते हों अथवा अनुसूचित जनजातियों के हों। इन लोगों को मकान बनाने के लिए कर्ज दिया जाना चाहिये, जिसकी वसूली किस्तों और ब्याज की रियायती दरों पर की जानी चाहिये।

४. सरकार द्वारा स्थानीय निकायों, औद्योगिक इकाइयों-सरकारी और निजी दोनों-और पंचायत समितियों को अपने कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के लिए आवास कार्यक्रम आरम्भ करने में सहायता दी जानी चाहिये।

५. सरकार को ऊसर भूमि पर ईंट के भट्टे बनाने और मकानों के लिए जमीन निकालने तथा मकानों के निर्माण के लिए आसान कायदे-कानून बनाने चाहिये।

६. कस्बों, शहरों और गाँवों में खाली पड़ी जमीन के मालिकों से कहा जाना चाहिये कि एक उचित अवधि में वे अपनी जमीन पर मकान बना लें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य, नगरपालिका अथवा पंचायत, जो भी हो, द्वारा ऐसी जमीन जब्त की जानी चाहिये। इस तरह जमीन की किल्लत दूर करने, किराये को घटाने और यहाँ तक कि जमीन की कीमतों को एक हद तक कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। घनी बस्तीवाले कस्बों और शहरों में न केवल आवास निर्माण की अधिकतम सीमा, बल्कि अल्पतम सीमा भी निर्धारित करना आवश्यक है, ताकि भू-कायदा सम्भव लाभकर उपयोग हो सके और इन इलाकों में आवास निर्माण का काम तेजी के साथ बढ़ सके।

७ निम्न आय वर्गों, श्रमिकों, कृषकों, हरिजनों और जनजातियों के लोगों के लिए सचमुच काम करनेवाली आवास सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता तथा आवास सामग्री और साथ ही आवास स्थलों की उपलब्धि के मामले में उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

स्वास्थ्य और शिक्षा

स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में राष्ट्र को अपने बालकों पर सर्व प्रथम ध्यान देना चाहिये। अवसर की समानता जन्म से शारम्भ होनी चाहिये। बालक को पौष्टिक आहार, उसके स्वास्थ्य की उन्नति, उसकी शिक्षा, एक माने में राष्ट्र की अवनति न होने देने के लिए एक प्रकार का सामाजिक बीमा है। इस सदर्भ में विशेषाधिकारों से वंचित लोगों के बच्चों को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के बच्चों के लगभग बराबर लाने के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिये।

पाँचवी योजना के अन्त तक सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा नि शुल्क और अनिवार्य हो जानी चाहिये। राष्ट्र की औसत पारिवारिक आय से कम आयवाले लोगों के सभी बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा नि शुल्क मिलनी चाहिये और उच्चतर शिक्षा सभी होनहार बच्चों को नि शुल्क प्राप्त होनी चाहिये। नि शुल्क शिक्षा में नि शुल्क पुस्तकें, मध्य-दिवस आहार और साथ ही अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के बच्चों, खास तौर पर उनकी लड़कियों, के लिए वस्त्रों की प्राप्ति भी शामिल होनी चाहिये। उच्चतर श्रेणी में नि शुल्क शिक्षा के अधीन पुस्तकों की उपलब्धि और छात्रावास का व्यय शामिल होना चाहिये। तकनीकल शिक्षा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भर्ती होनेवाले उन बालकों को नि शुल्क शिक्षा का लाभ प्राप्त होना चाहिये, जिनके माता-पिता की आय राष्ट्र की औसत पारिवारिक आय से कम है।

कृषि उत्पादन की वृद्धि की हमारी योजना में हमने श्रमिकों के अपने निजी गुणों पर कभी ध्यान नहीं दिया। बहुधा लोग यह भूल जाते हैं कि कृषि उत्पादन बहुत कुछ श्रमिकों के अपने गुणों पर निर्भर करता है। अतः

कृषि विकास और नये वैज्ञानिक तरीकों को काम में लाने की दृष्टि से कृषि कर्म करनेवाले श्रमिकों के प्रशिक्षण और साज-सामान का बहुत महत्व है। साथ ही खेती पर बहुत अधिक लोगों की निर्भरता को भी कम करना जरूरी है। इस दृष्टि से कृषि कर्म करनेवाले श्रमिकों को ग्रामोद्योग के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग और उपभोक्ता उद्योगों तथा साथ ही अन्य सहायक उद्योगों के क्षेत्र में नयी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

कृषि कर्म करनेवाले श्रमिक

अतः इस समस्या को हल करने के लिए एक दोहरा सुझाव दिया जा रहा है

- १ कृषि कर्म करनेवाले मजदूरों को कृषि-योग्य पडती भूमि पर बसाना और उन्हें कृषि-उत्पादन की उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण देना, तथा
- २ ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए कृषि श्रमिकों का प्रशिक्षण और उनकी भर्ती।

यदि इस समस्या को सतोषजनक रूप से हल करना है तो इन दोनों तरीकों को एक साथ अपनाना होगा। हमारा सुझाव है कि आगामी दो वर्षों में इस काम के लिए उचित आधार बनाया जाय। ऊपर लिखे अनुसार श्रमिकों को बसाने और उनके प्रशिक्षण से कृषि सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलेगी और ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण तथा साज-सामान की पूर्ति से खेती पर बसर करनेवालों की सख्या में कमी होगी। इस कोशिश के साथ-साथ न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम भी लागू किया जाना चाहिये, ताकि इस अंतराल में भी कृषि कर्म करनेवाले श्रमिकों की अवस्था में सुधार हो सके।

भारतीय राजनीति की असली कसौटी जन साधारण को अपनी नयी जिम्मेदारियों और साथ ही प्राप्त अवसरों के प्रति सजग कराने तथा राष्ट्रीय प्रयासों में उन्हें जुटाने की सामर्थ्य है। एक नयी सामाजिक व्यवस्था कायम करना तब तक संभव नहीं, जब तक कि जन साधारण उसे समझ-बूझ कर स्वीकार न करे और उसे अपनी निजी जिम्मेदारी न समझे।

गाँव और शहर

वैकुण्ठ ल. मेहता

गाँवों में बेरोजगारी का स्वरूप, साधारणतया इस शब्द के जो माने होते हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है। निश्चय ही गाँवों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं—खास कर गैर खेतिहर उत्पादकों में—जिनके पास साल भर काम नहीं रहता। ऐसे भी बहुत-से आदमी हैं जिनके पास वर्ष में महीनो काम नहीं होता। और फिर, ऐसे लोग हैं जिनके पास काम है, लेकिन पूरे दिन भर का नहीं। इन अन्तिम श्रेणी के व्यक्तियों में कुछ के पास तो इस प्रकार का आंशिक काम पूरे वर्ष भर रहता है, जबकि कुछ के पास किन्हीं मौसमों में ही। रोजगारी की किसी भी ठोस नीति में इन सभी प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता-पूर्ति करनी होगी। इस दृष्टि से देखने पर यह शकाम्पद ही लगता है कि देश के समग्र गैर खेतिहर उत्पादन का स्वरूप भिलाई जैसा ही हो।

राज्य सभा में वित्त विधेयक पर हुई बहस के उत्तर में वित्त मंत्री श्री टी टी कृष्णामाचारी ने यह विचार प्रकट किया बताया कि देहाती क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच फिलहाल जो भेद है वह समाप्त हो सकेगा। अपने इस विचार के पक्ष में उन्होंने भिलाई के आस-पास हुए विकास का अपना अनुभव पेश किया। पौंच वर्ष पहले आज जहाँ भिलाई है, और जिसकी आबादी १४, ००० है, वह एक उबड़-खाबड़ उजाड़ खण्ड था। वित्त मंत्री के विचारानुसार अगर समूचे देश में 'भिलाइयो' की स्थापना हो सके तो स्पष्टतः समस्या का समाधान हमारी पहुँच के समीप होगा। उन्होंने कहा बताया कि केवल एक ही बाधा है। वह बाधा वे सीमाएँ हैं जिनके अन्तर्गत वित्त मंत्रियों को काम करना पड़ता है। सम्भवतः इन सीमाओं का मतलब भिलाई जैसे प्रतिष्ठानों का तीव्र गति से विकास करने के लिए वित्त मंत्रियों के पास वित्तीय स्रोतों की कमी से है।

भिलाई का उदाहरण

वित्त मंत्री के दिमाग में अक्सर ये किस प्रकार के

औद्योगिक विकास की तस्वीर है, वह ग्राम्य औद्योगीकरण के बारे में बोलते हुए उन्होंने भिलाई का जो विशिष्ट सन्दर्भ पेश किया उससे स्पष्ट है। जिस प्रकार के उद्योग का वे समर्थन करते हैं वह सार्वजनिक विभाग में होगा अथवा निजी विभाग में, वह भारी सामान तैयार करने वाला होगा या उपभोक्ता सामग्री बनायेगा, यह सब वित्त मंत्री के भाषण के प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं होता। लेकिन इसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि, उनके विचार से, ग्रामीण निश्चलता को दूर करने के लिए इस बात की जरूरत है कि गाँवों अथवा जगलों के बीच दीर्घ स्तरीय उत्पादन इकाइयों स्थापित की जाये और इन उद्योगों में काम करनेवालों से शहरी समुदाय विकसित किये जाये। यह दावा किया जाता है कि ये उद्योग गाँवों में लोगों को काम देगे और वातावरण में इस प्रकार का परिवर्तन लायेगे कि 'गाँव' और 'शहर' के बीच का भेद मिट जायेगा। इन नये बसे कस्बों में ग्रामीणों को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जैसी सभी शहरी सुविधाएँ मिलेगी। तथापि, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, भिलाई तक में भी भीड़-भाड़ और कच्ची

क्षोपडियाँ देखने में आती हैं।

सचमुच यह एक आदर्श चित्र है। इस प्रकार का चित्र सामने लाकर रख देनेवाली योजना स्वीकार करने में, वित्त मंत्री को भय है, जो चीज बाधक हो सकती है वह साधन-स्रोतों की कमी इतनी नहीं है, जितनी कि आवश्यक साधन-स्रोतों के वितरण में योजना अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार की अनिच्छा। भिलाई तथा अन्य इस्पात सयंत्रों पर देश को पूँजी व्यय के रूप में पाँच अरब रुपये लगाने पड़े हैं, तथा भिलाई की क्षमता का विस्तार करने में डेढ़ अरब रुपये और खर्च होंगे। केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए तृतीय पंच वर्षीय योजना में योजना के कुल १ खरब १६ अरब (११,६०० करोड़) रुपये के परिव्यय में से १२ अरब ६० करोड़ ६९ लाख रुपये का प्रावधान है। आम अपेक्षा यह है कि चौथी पाँचसाला योजना में इस योजना परिव्यय में कोई एक खरब (१०,००० करोड़) रुपये की वृद्धि हो सकती है। अगर इस अतिरिक्त धनराशि के साथ वित्त मंत्री के उक्त विचार को स्वीकार कर लिया जाता है, तो देश भर में 'भिलाइयों' की स्थापना करते हुए इस विचार को कार्यान्वित करने में साधन-स्रोतों की कमी से कोई मार्गावरोध नहीं आने चाहिये।

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का वैविध्यकरण

तथापि, यदि उपयुक्त विदेशी विनिमय सहित वित्तीय साधन-स्रोत उपलब्ध हो तब भी जो उपचार सुझाया गया है वह निश्चय ही उस रोग का निदान करने में असफल होगा जिससे वर्षों के सघन आयोजन के बावजूद हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था—और फलस्वरूप राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था—ग्रस्त है। योजना अधिकारियों ने—और उनके आर्थिक, सांख्यिकीय तथा प्रशासनात्मक सलाहकारों ने—अब तक यह दृष्टिकोण अख्तियार किया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को बहुमुखी बनाया जाय। देश की चार-पञ्चमाश आबादी देहातों में रहती

है। अपने जीविकोपार्जन के लिए वह कृषि पर निर्भर है। उसकी यह कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए इस वैविध्यपन की आवश्यकता है। जिन लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है, उन्हें अन्यान्य काम-धंधों में लगाकर उनकी सख्या और अनुपात में कमी करना आयोजित कार्यक्रम का एक प्रधान उद्देश्य है। पिछले तेरह वर्ष में निजी और सार्वजनिक विभागों में उद्योगों का विकास होते हुए और योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजन के निमित्त अच्छी-खासी रकम के वितरण के बावजूद यह अनुपात प्रायः एक समान ही रहा है। इसलिए योजना अधिकारी इस बात के पक्ष में हैं कि देहानी इलाकों में अनेक ऐसे कुटीर और लघु स्तरीय उद्योगों का विस्तृत व सघन विकास किया जाय कि गैर खेतिहर उत्पादन कार्य में काम करने के जरिये ग्रामीणों की आमदनी में बढ़ती हो।

दीर्घ स्तरीय उद्योगों में रोजगारी

तृतीय पंच वर्षीय योजना बनाते वक्त जिस ग्रामीण औद्योगीकरण के कार्यक्रम की कल्पना की गयी थी, उसका आधार यही था। ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल जो बेरोजगारी है उसके समाधान में तो वर्तमान बड़े उद्योगों को विभक्त करने या देहाती क्षेत्रों में स्थानांतरित करने से ही और न ही वहाँ दीर्घ स्तरीय बड़े उद्योग खोलने से कोई विशेष मदद मिल सकती है। इसके साथ ही यह भी कोई आवश्यक नहीं कि ऐसा करने से उपलब्ध कच्चे माल का बेहतरीन उपयोग हो सकेगा। गाँव और शहर के बीच व्यावसायिक सम्बन्धों में सुधार तो और भी कम हो सकता है।

रोजगारी सम्बन्धी नीचे जो आकड़े दिये गये हैं उनसे पता चलेगा कि समस्या जितनी बड़ी है उसकी तुलना में नये दीर्घ स्तरीय उद्योगों के खोलने अथवा वर्तमान बड़े उद्योगों का विस्तार करने से बहुत कम लोगों को काम मिल सकता है। इस प्रकार की रोजगारी प्रदान करने में भिलाई जैसे उत्पादक सामान तैयार

करनेवाले उद्योगों का योगदान, उनमें जो परिव्यय होता है उसकी तुलना में कम है। निम्न आकड़े इस कथन की पुष्टि करते हैं

	१९५१	१९५६	१९६१
	(हजार में)		
कारखानों में रोजगारी	२,९१४	३,४०२	३,९१२
सार्वजनिक विभाग के			
निर्माण उद्योगों में	३६१×	अप्राप्य×	
रोजगारी अप्राप्य			
	४१६××	६०३××	

× स्टैटिस्टिकल आउट लाइन ऑफ इण्डिया (टाटा इण्डस्ट्रीज)।

×× भारत पाकेट बुक ऑफ इकॉनॉमिक इन्फॉर्मेशन (वित्त मंत्रालय)।

तीसरी पाँचसाला योजना के अनुसार कुल १ करोड़ ४० लाख लोगों को रोजगारी प्रदान करनी है। उद्योग और खान कार्यों के जरिये रोजगारी प्रदान की जा सकेगी ७ लाख ५० हजार व्यक्तियों को।

गाँवों में बेरोजगारी

इसके अलावा गाँवों में बेरोजगारी का स्वरूप, इस शब्द का साधारणतया जो अर्थ होता है उससे बहुत भिन्न है। गाँवों में निश्चय ही ऐसे कुछ आदमी हैं जिन्हें साल भर काम नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति खास कर गैर खेतिहर उत्पादकों में मिलते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्ष में महीनों काम नहीं रहता, और फिर उन व्यक्तियों की संख्या है जिनके पास काम है लेकिन वह पूरे दिन भर का नहीं होता तथा वैसे भी कुछ के पास तो साल भर का होता है एवम् कुछ अन्यो के पास किन्ही मौसम-काः

में। निम्न तालिका में सांख्यिकीय शब्दावली में तत्सम्बन्धी चित्र प्रस्तुत है

प्रति सप्ताह कार्य-घण्टे

श्रम शक्ति (अंक दस लाख में)

७ घण्टे या काम	१८ ९
१४ " "	२४ ३
२८ " "	४० २
४२ " "	६४ ३
५६ " "	१०९ ७
७० " "	१३३ ४
पूरे सप्ताह का	१३८ ८

स्रोत - प्रोफेसर पी सी महालनोबीस का 'संख्या' में प्रकाशित अध्यक्षीय भाषण, खण्ड २०, भाग १ और २, सितम्बर १९५८।

किसी भी रोजगारी सम्बन्धी ठोस नीति को इन सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करनी होती हैं। इन व्यक्तियों के कौशल व अभिरुचि को भी ध्यान में रखना होगा। किसी ऐसे कार्यक्रम की अपेक्षा जो उच्च कौशल अथवा दूर-दूर के स्थानों से मगवायी गयी कच्ची सामग्री पर निर्भर हो, लोगों द्वारा उस कार्यक्रम के तुरन्त अपनाने की अधिक सम्भावना है जिसमें साधारण साधन-सरजाम की आवश्यकता हो तथा आसानी से मिलनेवाली कच्ची सामग्री का उपयोग।

ग्राम्य क्षेत्रों के अनुकूल नहीं

अन्त में, एक 'अच्छे जीवन' के दृष्टिकोण से—जिसे प्राप्त करना हमारे आयोजन का उद्देश्य है—यह गंका-स्पद ही है कि हमारा समूचा का समूचा गैर-औद्योगिक उत्पादन स्वरूप भिलाई जैसा ही हो। पूँजी परिव्यय के अलावा इस प्रकार के उत्पादन में अधिकार सकेन्द्रण भी है जो हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद अथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सम्बोध में ठीक नहीं बैठता। और फिर, बहुत ही छितरे बसे देहाती क्षेत्रों अथवा जगली

इलाको में जो बस्तियाँ बसती हैं उनमें वैसे व्यक्तियों को लाना पड़ेगा जो अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक से आकर्षित होते हैं। कभी-कभी—खास कर आदिवासियों के मामले में—इसका परिणाम निकलता है एक ऐसी सम्यता की जड़ काट देना, जो यद्यपि उनकी आर्थिक शोषण से रक्षा करने में उपयुक्त नहीं है, लेकिन शहरीकरण से पैदा होनेवाली बुराइयों के समान सामाजिक बुराइयों से उनकी रक्षा करती है।

ग्राम्य औद्योगीकरण कार्यक्रम जिस प्रकार का औद्योगिक विकास करना चाहता है, उसकी कल्पना केवल तीव्र आर्थिक विकास को उद्दीप्त करने के दृष्टिकोण से ही नहीं की गयी है। इस प्रकार का विकास धीरे-धीरे करके एक ऐसे आधार पर करने का इरादा है जो सम्बद्ध क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक वातावरण में समरसता

के साथ अर्थ-व्यवस्था का वैविध्यकरण सुनिश्चित करे। इसके अलावा काफी तादाद में लोगों को सघन औद्योगिक अभियान के फल चखने के लिए एक लम्बे समय तक बिना इन्तजार करवाये, इसमें उन्हें काम देने की आवश्यकता पूरी करने का महान लाभ निहित है। गन्दी बस्तियाँ बसती जाने की समस्या का एक ही समाधान है—रोज-गारी स्थल का शहरो से स्थानान्तरण, क्योंकि वैसा करने से ही गाँवों से शहरो की ओर जानेवाले जन-प्रवाह को रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम—जिसका पिछले महीने श्री जी रामचन्द्रन ने राज्य सभा में बड़े तर्क सगत रूप में समर्थन किया था—ही एक ऐसा कार्यक्रम है जोकि शहरीयों तथा ग्रामीणों दोनों का हित-साधन करता है।

बम्बई ३ मई १९६४

प्रायः ऐसा कहा जाता है कि शहरी लोग और उनका बौद्धिक वर्ग देहातो में गतिशीलता लाने का प्रयास करें, जिसका वहाँ अभाव है। लेकिन कठिनाई तो यह है कि भारत के साधारण गाँव और शहर के बीच, चाहे वह शहर किसी भी आकार का क्यों न हो, पाँच सौ या एक हजार वर्ष का अन्तर है। एक तरफ गाँवों में जहाँ आकांक्षाओं की भीति की कोई सरजमीं नहीं है, शहरो में असीमित लोलुपता का बोलबाला है। बनिया वर्ग और शहरो का नया धनी वर्ग लोभ के पीछे प्रायः उतना ही अंधा बन गया है, जितना ग्रामीण समुदाय परम्पराओं के पीछे बना हुआ है। सामाजिक चेतना के अकुर के लिए भारत की भूमि उर्वर नहीं है।

—वेलेस हैगेन . आफ्टर नेहरू, दू ?

रुपर्ट हार्ट-डेविस, लन्दन।

केरल में सहकार और कृषि उत्पादन

कृ. श्रीकण्ठन नायर

यद्यपि प्रथम पंच वर्षीय योजनावधि में केरल में सहकार के क्षेत्र में कोई द्रुत प्रगति नहीं हुई, तथापि अनुवर्ती पंच वर्षीय काल में इस आंदोलन को वेग मिला। इस अवधि में विक्रय-व्यवस्था में लगी प्राथमिक समितियों को भी शक्तिशाली बनाया गया। साथ ही साथ कृषि समितियों की स्थापना भी हुई।

प्रस्तुत लेख में केरल में कृषि उत्पादन पर पड़े सहकारी आन्दोलन के प्रभाव के सम्बन्ध में, खास कर प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से, संक्षेप में चर्चा की गयी है। कृषि उत्पादन में गिरावट की समस्या बड़ी गम्भीर है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा था, “इस देश में अगर कृषि क्षेत्र में नाकामयाबी मिलती है तो हम नाकामयाब होते हैं, सरकार नाकामयाब होती है, समूचा देश नाकामयाब होता है। खेती के मामले में कामयाबी हासिल करने के अलावा हमारे सामने अन्य कोई सहारा नहीं है।” राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्व सर्व विदित है और इस प्राथमिक उद्योग का विकास—जिसमें देश की करीब ७५ प्रति शत आबादी लगी हुई है—करना आर्थिक विकास का केन्द्र बिन्दु है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ राष्ट्र ने पंच वर्षीय योजनाओं के रूप में एक भली भाँति सोचा-समझा आयोजित विकास का कार्यक्रम अपनाया है। फिलहाल तीसरी पाँचसाला योजना चल रही है, जिसका आधे से ज्यादा काल पूरा हो चुका है। प्रथम पंच वर्षीय योजना का उद्देश्य आवश्यक रूप से ही कृषि-विकास था। उद्योग, शक्ति, यातायात आदि जैसे अर्थ-व्यवस्था के अन्य विभागों के लिए धनराशि का वितरण काफी कम था। द्वितीय योजना में कृषि पर बराबर का जोर नहीं दिया गया। परिणाम यह निकला कि कृषि उत्पादन में कुछ गिरावट आ गयी। तृतीय पंच वर्षीय योजना बनाते वक्त यह कमी महसूस की गयी और उसमें कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को उपयुक्त महत्व दिया गया।

ग्रामीण आबादी का मुख्य पेशा कृषि के विकास के अलावा लघु उद्योग, प्रशोधन, विक्रय-व्यवस्था, वितरण आदि जैसे अन्य कामों को भी सहकारी आधार पर संगठित तथा विकसित करना होगा। ग्रामीण अवस्थाओं में पुनर्गठन और सुधार करने के लिए सहकारी आन्दोलन सर्वाधिक उपयुक्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सहकार को सामाजिक संगठन की नीति और सिद्धान्तों के आधार के बतौर स्वीकार किया है। कांग्रेस द्वारा नागपुर अधिवेशन (१९५९) में पारित प्रस्ताव के अनुसार समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना, ग्राम सहकारिताओं और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देते हुए करनी है। ग्राम स्तर पर सभी विकासात्मक गतिविधियों के क्षेत्र में इन दो संस्थाओं का प्रमुख स्थान होना चाहिये। ग्राम सहकारी समिति कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए उधार और अन्य सेवाएँ प्रदान करने के अलावा कृषि उत्पादन के संग्रहण, भाण्डारीकरण तथा विक्रय-व्यवस्था का प्रबन्ध भी करेगी।

अन्य क्षेत्रों तक विस्तार

भारत में साठ वर्ष पूर्व प्रारम्भ सहकार आन्दोलन हाल ही तक कृषि विभाग तक ही सीमित रहा है और वह भी मुख्यतः कृषि कार्यों के लिए उधार देने तक ही। कृषि क्षेत्र के अन्य कामों तक उसका विस्तार बाद में हुआ। इस प्रकार विक्रय-व्यवस्था, कृषि (फार्मिंग) तथा अन्य ऐसे ही कामों सम्बन्धी सहकारी समितियों के संगठन ने हाल के वर्षों में ही महत्व प्राप्त किया है—खास कर पंच

वर्षीय योजनाओं के श्रीगणेश के समय से। एक अदने किमान के पाम खेती करने की लागत वर्दास्त करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं होती। फिलहाल उत्पादन चालू रखने के लिए किसान को आवश्यक उधार प्रदान करने के लिए सहकारिता सर्वाधिक अनुकूल अभिकरण है। कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषक की हालत में सुधार करने के लिए उधार के अलावा, उन्नत बीजों, अच्छे उर्वरकों तथा किसानों द्वारा अपनाये जानेवाले उन्नत तौर-तरीकों की जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना भी परमावश्यक है। किमान एक बार सहकारी जमा पहन लेता है तो ये सब बातें उसकी पहुँच के अन्दर आ जाती हैं। इसी प्रकार सहकारिताओं को किसान के अतिरिक्त माल की बिक्री करने का काम भी सौपा जा सकता है। इस प्रकार गाँव में काम करनेवाली प्राथमिक सहकारिता, किसान को अपनी रोजमर्रा की समस्याएँ हल करने में अनेक प्रकार से सहायता देती है।

केरल की स्थिति पर नजर डालने से पता चलेगा

कि राज्य की कृषिक अर्थ-व्यवस्था कुछ मामलों में अपनी विशिष्टता रखती है। केरल में खेती पर निर्भर करनेवाली आबादी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उससे होनेवाली आमदनी राज्य की कुल आय का तीन-पंचमाश है। केरल में प्रति व्यक्ति कृषिक आय २४३ रुपये है, जोकि राष्ट्रीय औसत (१८८ रुपये) से काफी अधिक है। दूसरी विशेषता यह है कि रबड़, कागज, आदि जैसी नकद फसलों के मामले में केरल का प्रायः एकाधिकार है। इन नकद फसलों के उत्पादनों का विदेशों को निर्यात होता है, जिससे काफी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भूमि पर अत्यधिक दबाव का परिणाम निकला है, खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाना। केरल में प्रति व्यक्ति कृष्ट भूमि बहुत ही कम है—केवल २५ सेण्ट। आबादी बढ़ने और खेती के लिए नयी भूमि प्राप्त करने की गुंजाइश न होने की वजह से यह समस्या और भी गम्भीर होगी। तालिका १ में उपलब्ध भूमि के उपयोग से सम्बन्धित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका १

केरल में भूमि उपयोग

(क्षेत्र हजार एकड़ में)

उपयोग का प्रकार	५०-५१	५५-५६	६०-६१	५०-५१ से ६०-६१ में वृद्धि (+) या कमी (-)
जंगल	२,१२१	२,४३३	२,६१०	+ ४८९
गैर खेतिहर उपयोग के अन्तर्गत भूमि	४६६	४७१	५०६	+ ४०
बजर और अकृष्ट भूमि	५९६	४९७	३७४	- २२२
स्थायी चरागाह तथा अन्य ऐसे ही स्थल	१०१	११६	११२	+ ११
विविध प्रकार के वृक्षारोपण के अन्तर्गत भूमि	४३०	५०८	५०५	+ ७५
कृषि योग्य बेकार पड़ी जमीन	७२०	४०६	३५४	- ३६६
मौजूदा पडती के अलावा अन्य पडती भूमि	२२७	३६४	१५४	- ७३
वर्तमान पडती भूमि	११५	१४०	१६६	+ ५१
विशुद्ध जोत भूमि	४,२८९	४,४७७	४,७५४	+ ४६५
कुल फसली क्षेत्र	४,९७५	५,४६६	५,८०४	+ ८२९
दोहरी फसल का क्षेत्र	६८६	९८९	१,०५०	+ ३६४

टिप्पणी सन् १९६०-६१ के आकड़ों के अनुसार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र ६५,३५,००० एकड़ है।

तालिका १ से प्रकट होता है कि दूसरी पाँचसाला योजना के दौरान बोआई की गयी जमीन के क्षेत्र में ४,६५,००० एकड़ की वृद्धि हुई है। आलोच्य दस वर्ष की अवधि में फसलो के अन्तर्गत की भूमि में भी बढ़ती हुई है। तालिका से यह तथ्य भी सामने आता है कि नयी जमीन पर जुताई की गयी है जोकि इससे स्पष्ट होता है कि बजर, अकृष्य और कृष्य पडती भूमि के क्षेत्र में कमी हुई है। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय दोनों ही योजनाओं की अवधि में कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ा है।

क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

राज्य की कृषिक अर्थ-व्यवस्था का विश्लेषण करते वक्त यहाँ पर केरल में मुख्य फसलो के क्षेत्र, उत्पादन और प्रति एकड़ उपज का एक सही चित्र सामने रखना गार्थक होगा।

नारियल, गन्ने और काजू जैसी फसलो की कृषि के क्षेत्र तथा उत्पादन दोनों में एक साथ वृद्धि हुई है। टेपिओका, नारियल, काजू, काली मिर्च, अदरक, हल्दी और गन्ने जैसी फसलो की उत्पादकता में गिरावट आयी है। असल में तालिका २ द्वितीय पंच वर्षीय योजनावधि में प्राप्त सफलताओं का सही चित्रण प्रस्तुत करती है। यह देखा जा सकता है कि चावल, टेपिओका, गन्ना, केला, काजू आदि का उत्पादन बढ़ा है। चावल के मामले में, जोकि यहाँ का प्रधान भोजन है, १ लाख ८२ हजार टन की वृद्धि हुई है, जोकि द्वितीय योजना के दौरान प्राप्त किये जानेवाले लक्ष्यांक के ५० प्रति शत से कुछ अधिक है। चावल उत्पादन १९५०-५१ में ६ लाख १ हजार टन था। उसका उत्पादन बढ़ कर १९५५-५६ में ८ लाख ७० हजार टन हुआ और १९६०-६१ के आकड़ों के अनुसार कुल उत्पादन १० लाख ५१ हजार टन हुआ। खाद्यान्नों-

तालिका २

केरल में प्रमुख फसलो के अन्तर्गत भूमि, उत्पादन और प्रति एकड़ उपज १९५५-५६ और १९६०-६१

फसल	क्षेत्र (हजार एकड़ में)		उत्पादन (हजार टन में)		प्रति एकड़ उपज (पौण्ड में)	
	५५-५६	६०-६१	५५-५६	६०-६१	५५-५६	६०-६१
चावल	१,८७६ ४०	१,९२४ ७३	८७० ००	१,०५० ७२	१,०३९	१,२२३
दाल	११० ५८	१०९ ०२	१७ २८	१७ २७	३५०	३५५
टेपिओका	५४८ ९०	५९८ ४९	१,५६९ ००	१,६५६ ५०	६,४०३	६,२००
नारियल*	१,१०६ ८९	१,२३७ ४०	३,०९९ ००	३,२२० ००	२,८००	२,६०२
सुपारी*	१४३ ५६	१३७ ०७	६,४६० ००	७,७३७ ००	४४,९९९	५७,७०९
काजू	९२ ५८	१३४ २२	५७ ८६	८३ ३०	१,४००	१,३८९
केला	११६ ३०	१०९ ७७	३११ ७९	३२२ ६९	६,००५	६,५८५
इलायची	६९ ३६	७० ६९	१ २४	१ २६	४०	४०
काली मिर्च	२१३ ७१	२४६ ५०	२७ २४	२६ ६०	२८६	२४२
अदरक	२५ ८३	२९ ६६	१० ९४	११ ०९	९४९	८३७
हल्दी	११ २५	११ ५३	५ ०२	४ १२	१,०००	८००
गन्ना	१८ ०२	२२ ६०	३३४ ४७	३३४ ९०	४१,५७७	३७,१५८

* उत्पादन दस लाख की संख्या में और प्रति एकड़ औसत उत्पादन सामान्य संख्या में दिया गया है।

जैसा कि तालिका २ में दिये गये आकड़ों से स्पष्ट है, १९५५-५६ से १९६०-६१ की अवधि के दरमियान जैसा कि तालिका २ में दिये गये आकड़ों से स्पष्ट है, १९५५-५६ से १९६०-६१ की अवधि के दरमियान त्पादन के मामले में केरल अभाव-ग्रस्त क्षेत्र है। प्रति प्रौढ व्यक्ति प्रति दिन १४ औंस के हिसाब से वार्षिक

आवश्यकता १९ लाख ८० हजार टन चाबल है। अगर इस सम्बन्ध में राज्य को आत्मनिर्भर बनना हो तो उत्पादकता काफी बढ़ानी पड़ेगी व सधन कृषि करनी होगी।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में विकास की प्राप्ति के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए कृषि विभाग को सुव्यवस्थित आधार पर पुनर्गठित करना पड़ेगा। तत्सम्बन्धी प्रयास स्वेच्छिक होने चाहिये, क्योंकि केवल तभी सर्वोत्तम फल-प्राप्ति हो सकती है। यह महसूस किया जाता है कि सगठन सहकारी होना चाहिये। ऐसा करना राष्ट्र के लोकतांत्रिक आयोजन के सिद्धान्त में विशेष रूप से सागोपाग है। इसके अलावा आयोजित विकास का उद्देश्य है समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना। पंच वर्षीय योजनाओं में सहकारी आन्दोलन को सौपी गयी भूमिका उल्लेखनीय है। तीसरी पंचसाला योजना में सहकारी उधार, प्रशोधन, विक्रय-व्यवस्था, आदिकी व्यवस्था के लिए धनराशि काफी बढ़ायी गयी है।

केरल में १९५१-५६ की अवधि में सहकार के क्षेत्र में कोई तीव्र प्रगति नहीं हुई। प्रथम योजना में प्राथमिक समितियों को पुनर्गठित तथा पुन अनुप्राणित करने के सम्बन्ध में कोई लक्ष्यांक निर्धारित नहीं किया गया। प्रथम योजना में सहकार सम्बन्धी योजनाओं के लिए मात्र आठ लाख रुपये परिव्यय स्वरूप रखे गये। योजना के दौरान करीब एक-चतुर्थांश ही खर्च हुआ। जिन नयी सस्थाओं का सगठन किया गया और जिन्होंने काम करना शुरू किया उनमें १५ ग्राम बैंक, ३५ विक्रय व्यवस्था समितियाँ, २० कृषि समितियाँ, और ३६ बहुदेशीय सहकारी समितियाँ थी। प्रथम योजना के अन्त में कुल ३,१०४ समितियाँ थी। इनकी सदस्य-संख्या ४,८३,११३ थी। एक अनुमान के अनुसार राज्य में बसे हुए प्रति २ ७५ वर्ग मील क्षेत्र पीछे एक सहकारी समिति थी और प्रति १५ वयस्को के पीछे एक सदस्य था।

सहकारी आन्दोलन के विकास का जहाँ तक सम्बन्ध है, द्वितीय योजना-काल अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल था। उधार और विक्रय-व्यवस्था समितियों के विकास पर

जोर दिया गया। वास्तव में इनके विकास पर इस प्रकार के जोर का दिया जाना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा नियुक्त ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों का फल था। केरल केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक तथा दस प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों के गठन के अलावा द्वितीय योजनावधि में ही त्रावणकोर कोचीन राज्य सहकारी बैंक को केरल राज्य सहकारी बैंक का रूप दिया गया और जिला स्तर पर केन्द्रीय बैंकों की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त किसानों की हालत में सुधार और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से १२६ नयी सहकारी समितियाँ बनायी गयी।

तालिका ३ राज्य में ६०-६१ के दौरान कृषि उधार समितियों का काम सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका ३

केरल में कृषि उधार समितियों का कार्य-चालन १९६०-६१

कृषि उधार समितियों की कुल संख्या	२,२३९
सदस्य संख्या	७,९८,१०८
चुक्ता हिस्सा पूंजी (रुपये)	१,७४,५१,७५०
विधिविहित आरक्षण (रुपये)	६३,१३,७०८
अन्य आरक्षण (रुपये)	३५,७९,२९३
सदस्यों व अन्य व्यक्तियों की जमा पूंजी (रुपये)	१,२१,८०,१६२
अन्य उधार (रुपये)	२,७८,७५,४५६
संचालन पूंजी (रुपये)	६,७४,००,३६९
वर्ष के दौरान दिया गया ऋण (रुपये)	५,०८,८५,५७०
वर्ष के अन्त में बकाया ऋण (रुपये)	५,१३,५५,१३३
लाभ कमानेवाली समितियों की संख्या	१,६०६
वर्ष का विशुद्ध लाभ (रुपये)	१४,८७,१७४
घाटे में रही समितियों की संख्या	५६७
घाटा रहा (रुपये)	४,३५,७३८

स्रोत सहकार विभाग की १९६०-६१ के लिए 'एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट', पृष्ठ २४।

उक्त प्रगति के अलावा इसी अवधि में विक्रय-व्यवस्था के क्षेत्र में काम करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को शक्तिशाली बनाया गया। सैतीस प्राथमिक विक्रय-व्यवस्था समितियों, एक प्रशोधन समिति और एक शीर्ष विक्रय-व्यवस्था समिति का गठन किया गया। केरल में कृषि विक्रय-व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएँ हैं। चूँकि कृषि उत्पादन में अधिक हिस्सा नकद फसलों का है, इसलिए इस सम्बन्ध में एक प्रभावक तत्त्व का होना अत्यावश्यक है कि उत्पादक को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले। जिन वस्तुओं का विदेशों को निर्यात होता है उनके सम्बन्ध में ये कदम उठाये जाने चाहिये उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाय, उनका गुण-स्तर कायम रखा जाय, उनमें मिलावट रोकी जाय, आदि।

कृषि उत्पादन की विक्रय-व्यवस्था

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सहकारी समितियाँ ये सब जिम्मेदारियाँ बड़ी अच्छी तरह निभा सकती हैं। लेकिन यह एक निरुत्साहित करनेवाली बात है कि केरल में कृषि उत्पादनों की विक्रय-व्यवस्था के सम्बन्ध में सहकारी समितियाँ कोई विशेष उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभा रही हैं। जितने नारियल बिकते हैं, उनका १४ प्रतिशत ही सहकारी समितियों के जरिये बिकता है। बिक्री समितियों के जरिये बेची जानेवाली अन्य दो प्रकार की सामग्री के सम्बन्ध में यह कि सुपारी की कुल मात्रा में से १७ प्रतिशत और काली मिर्च के कुल परिमाण का ५२ प्रतिशत ही इनके मार्फत बिकता है। वर्ष १९६०-६१ में ७२ प्राथमिक कृषि सहकारी विक्रय समितियाँ थी। उनकी सदस्य संख्या २१,६४१ थी। उनकी कुल हिस्सा पूँजी ११ लाख ३४ हजार रुपये थी। इसमें राज्य सरकार का योगदान ३ लाख ६० हजार रुपये के बराबर था। उन्होंने कुल ४३ लाख ८७ हजार रुपये मूल्य के कृषि उत्पादन की बिक्री की तथापि, प्रत्येक कृषक

के बिक्री योग्य अतिरिक्त माल की निकासी के लिए और अधिक विक्रय-व्यवस्था समितियाँ सगठित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

सहकारी कृषि

द्वितीय योजनावधि में कुछ सहकारी कृषि समितियाँ बनायी गयीं। कृषि में उत्पादन की निजी इकाई बहुत ही छोटी है, जिसका परिणाम निकला है अलाभदायक कृषि। केरल में जितनी जमीन पर वास्तव में खेती होती है उसमें प्रति खेत का औसत क्षेत्रफल मुश्किल से २५ सेण्ट ही है। इसलिए बुनियादी समस्या ऐसे किसानों की है, जिनके पास भूमि बहुत कम है अथवा है ही नहीं। अतएव सवाल यह है कि उन अधिकांश किसानों की हालत कैसे सुधारी जाय, जो या तो भूमिहीन हैं अथवा जो अलाभदायक छोटे-छोटे अलग-अलग स्थानों में अवस्थित खेतों पर निर्भर करते हैं? ऐसी अवस्था में कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय? इसका एक ही जवाब है—सहकारी कृषि अपनाना।

राज्य में १९६०-६१ में २१ संयुक्त कृषि समितियाँ और तीन सामूहिक कृषि समितियाँ थी। इनके अलावा १०६ उन्नत कृषि समितियाँ और दो सिकमी काश्तकार समितियाँ थी। इन सब समितियों की सदस्य संख्या १४,००६ थी और हिस्सा पूँजी ४ लाख ४६ हजार रुपये। उनके पास की कुल ११,१५४ एकड़ भूमि में से १०,९०५ एकड़ जमीन पर खेती होती थी। वर्ष १९६०-६१ के दौरान कुल उत्पादन १० लाख ८९ हजार रुपये का हुआ। तृतीय पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में ९० समितियाँ शुरू करने के कार्यक्रम के साथ एक-एक मार्गदर्शी परियोजना प्रारम्भ करने की व्यवस्था है। इस प्रकार नौ जिलों में नौ मार्गदर्शी परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी।

बचीलन ३० अप्रैल १९६४

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

चित्तूरी वेकट राघवुलू*

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के कार्यक्रम से एक ओर महान आशाओं का संचार हुआ है तो दूसरी तरफ नयी-नयी कठिनाइयाँ खड़ी हुई हैं। गांवों में निम्न आर्थिक स्तर, नागरिक जागरूकता का अभाव, राजनैतिक अपरिपक्वता और अगुआई की अत्यधिक कमी जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान पर ही पंचायत राज से की जानेवाली अपेक्षाओं की पूर्ति निर्भर है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत जैसे देश में किसी भी

राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का मुख्य केन्द्र बिन्दु ग्राम समाज होना चाहिये। इस अकाट्य तथ्य को महसूस करते हुए प्रथम पंच वर्षीय योजना के अग स्वरूप सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में सुधार करने के उद्देश्य से किये जानेवाले प्रयासों को गति प्रदान की और जिला प्रशासन में नव प्राण फूँके। सरकार से वित्तीय और प्राविधिक सहायता प्राप्त करते हुए 'अपनी सहायता आप करो' के कार्यक्रम के जरिये ग्राम समाज के सामाजिक जीवन में चतुर्दिक सुधार लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। फिर भी, कार्यक्रम के सामयिक मूल्यांकन से इस बात का संकेत मिलता है कि यह वांछित लोक-भागीदारी जागृत करने में असफल रहा है और अभिक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रहा है।

मेहता दल की सिफारिशें

बलवतराय मेहता अध्ययन दल^१ ने वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया। दल ने विकास कार्यक्रमों के बनाने

और चलाने में जन-प्रतिनिधियों को शामिल न करना इस आन्दोलन की असफलता का कारण ठहराया। इसलिए दल ने ग्राम, खण्ड और जिला स्तरों पर ऐसी प्रतिनिधि संस्थाओं के निर्माण की सिफारिश की, जो विकास कार्यों में लोक अभिरुचि तथा लोक-अभिक्रम जागृत करने में समर्थ होगी। इसके अतिरिक्त यह सिफारिश भी की गयी कि इन संस्थाओं को पर्याप्त धन-राशि और राजस्व के साधन-स्रोत प्रदान करने चाहिये ताकि ये अपना उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ हो सके। इस सांस्थानिक व्यवस्था को पंचायत राज अथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कहा गया है।

यहाँ मौजूदा पंचायत राज और गांधीवादी तथा सर्वोदयी पंचायत राज के सम्बोधों का विभेद स्पष्ट करना समीचीन होगा। महात्मा गांधी ने स्वायत्त और आत्म-निर्भर ग्राम समाज का निर्माण करने पर जोर दिया। गांधीजी के इस विचार को लेकर श्री जयप्रकाश नारायण^२ परिपूर्ण विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हैं। प्रत्येक स्तर पर लोगों को, जो काम

* प्रस्तुत लेख के लिखने में आश्रित विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में 'रीडर' डॉक्टर आर. बी. चंद्रशेखर राव ने जो प्रोत्साहन और उपयोगी सुझाव दिये उसके लिए लेखक उनका आभारी है।

१ योजना आयोग (भारत सरकार) की योजना परियोजना समिति 'सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर अध्ययन दल का प्रतिवेदन', खण्ड २, नयी दिल्ली, १९५७।

२ नयी दिल्ली से प्रकाशित दि. इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन (जुलाई-सितम्बर १९६१, वर्ष ७, अंक. ३, पृष्ठ २७१-२८१) में श्री जयप्रकाश नारायण. 'डीसेण्ट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी थियरी एण्ड प्रैक्टिस,' मो. क. गांधी पंचायती राज, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, १९५९, अध्याय ३ और ४।

करने में वे समर्थ हो उनके लिए आवश्यक सभी अधिकार दिये जाने चाहिये और केवल वे ही काम उच्चतर स्तर पर करने के लिए दिये जायें जो निचले स्तर पर नहीं किये जा सकें। प्रत्येक स्तर पर की सस्था स्वयम् में एक सरकार है। कोई भी सस्था एक-दूसरी से ऊपर नहीं होगी।

अलगाव की स्थिति मिटाना

इस प्रश्न पर विचार करते वक्त यह याद रखना चाहिये कि हमारे गाँवों में गुटबन्दी, जातिवाद आदि जैसी विरोधात्मक बातें कोई अपवाद न हो कर सामान्य रूप से पायी जानेवाली बातें हैं। और फिर, गाँव अब आत्म-निर्भर तथा अलगाव की स्थिति में रहनेवाली इकाइयाँ नहीं रहे, वे राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रवाहों के अभिन्न अंग हैं। पिछले एक सौ वर्ष में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों ने अलगाव की स्थिति में रहनेवाले गाँवों का जीवित रहना असम्भव बना दिया है। उनका अलगाव कई तरह से मिटा दिया गया है — राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन और अन्य इसी प्रकार के सघ बना कर, सामाजिक क्षेत्र में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने-आने में सक्रिय बना कर, तथा आर्थिक क्षेत्र में विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी में सुधार ला कर।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४० में राज्य को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वह "ग्राम पंचायतें संगठित करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्ति प्रदान करने के लिए कदम उठाये।"

पंचायत राज लोकतंत्र और विकास दोनों से सम्बद्ध हैं। लोगों को अधिकाधिक सख्या में विकासात्मक कामों में लगाना तथा लोकतंत्र की प्रक्रिया में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आयोजन की प्रक्रिया में स्थानीय आबादी को शामिल किया जाय। जैसा कि स्वर्गीय

श्री बी टी कृष्णमाचारी ने कहा था, "सबसे आवश्यक बात यह है कि प्रत्येक स्थान पर ग्रामीणों को स्वयम् अपना निर्णय लेने में और ऐसे कामों में अपना यथा शक्य स्वेच्छिक श्रम प्रदान करने में समर्थ बनाया जाय, जिनसे समूचा समुदाय लाभान्वित हो। कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि देश के लाखों-करोड़ों छोटे-छोटे किसान उसके उद्देश्य स्वीकार न कर ले, उसके बन्दों में उनका हाथ न हो, उसे अपनी ही योजना न समझे, और उसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक त्याग व बलिदान करने के लिए तैयार न हो।"^३ इस प्रकार नीति निर्धारक ग्राम समाज में सोच समझ कर अपने प्रगतिशील विचार भरने की कोशिश करते वक्त ग्राम समाज के गठन पर उन परम्परागत मूल्यों के काबू अथवा नियंत्रण का भी ध्यान रख सकते हैं, जिनका प्रशासन की प्रक्रिया में उन्हें सामना करना पड़ेगा।

पंचायत राज कानून

बलबन्तराय मेहता दल के प्रतिवेदन के बाद विभिन्न राज्यों में पंचायत राज के सम्बन्ध में कानून बने। किसी एक ही पद्धति का अनुसरण करने के लिए राज्यों पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राज्य को स्थानीय अवस्थाओं के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त प्रणाली के विकास का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये। तथापि, भारत सरकार ने कुछ बुनियादी सिद्धान्तों का अनुकरण करने पर जोर दिया। इन मूलभूत सिद्धान्तों में ये बातें शामिल थीं - त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वायत्त-शासन संस्थाओं की स्थापना, जिनमें परस्पर जीता-जागता सम्बन्ध हो, इन संस्थाओं को सही रूप में शक्ति तथा उत्तरदायित्व सौंपना, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त साधन-स्रोतों का स्थानान्तरण और सभी विकास कार्यक्रमों का इन

३ भारत सरकार के सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय द्वारा नयी दिल्ली में १९५७ में आयोजित षष्ठम विकासायुक्त सम्मेलन में श्री बी टी कृष्णमाचारी द्वारा दिया गया भाषण, पृष्ठ २१।

पंचायत राज सस्थाओं के जरिये कार्यान्वयन। इस प्रकार निरूपित व्यवस्था ऐसी होगी कि उससे धीरे-धीरे करके भविष्य में शक्ति और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण तथा विस्फुरण में सुभीता होगा।

ग्यारह राज्यों में—असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान में—पंचायत राज लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में तत्सम्बन्धी कानून बन चुके हैं। केरल तथा जम्मू और कश्मीर में कानून बनाये जा रहे हैं।

पंचायत राज का गठन

यहाँ विभिन्न राज्यों में पंचायत राज का जो स्वरूप है उसका एक स्थूल स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत नामक दो सस्थाएँ हैं। ग्राम सभा में कुछ राज्यों में वे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें भूतधिकार प्राप्त है और कुछ राज्यों में सभी प्रौढ व्यक्ति शामिल हैं। पंचायत के अनुमान-पत्रक, वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन और क्षेत्र में चलाये जानेवाले विकास कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करना ग्राम सभा के कार्य है। व्यवहार में ग्राम सभा एक प्रभावहीन सस्था पायी गयी है। ग्राम समाज इस सम्बन्ध में बड़ा उदासीन रहा है और फलस्वरूप ग्राम सभा की नियमित बैठके नहीं हो सकी। ग्राम सभा के संचालन पर हाल ही में एक अध्ययन दल^४ ने सुझाया है कि 'लोक भागीदारी लोकतंत्र' का विकास करने के लिए ग्राम सभाओं को पंचायत राज में अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये तथा उन्हें पंचायतों के काम का मूल्यांकन करने का अधिकार भी देना चाहिये।

ग्राम पंचायत, पंचायत राज की बुनियादी इकाई है।

४ 'पंचायत राज आन्दोलन में ग्राम सभा की स्थिति का अध्ययन करनेवाले दल का प्रतिवेदन,' सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय (भारत सरकार), नयी दिल्ली; अप्रैल १९६३।

५ यहाँ यह बताया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल पंचायत

इसका चुनाव ग्राम सभा करती है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका है। इसका आकार आबादी पर निर्भर करता है। असम तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में पंचायतों के सदस्यों—पंचों—का चुनाव गुप्त मतदान से होता है। असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरपंचों व उप सरपंचों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है, जबकि अन्य राज्यों में उनका चुनाव पंचायत के सदस्य अपने में से करते हैं। पंचायतों को अनेक प्रकार के काम सौंपे गये हैं। पारम्परिक नगरपालिका सम्बन्धी कामों के अलावा उन्हें सामाजिक, विकासात्मक और सांस्कृतिक कार्य भी सौंपे गये हैं।

पंचायत समिति के कार्य

पंचायत राज के सघटन में बीच के स्तर^५ पर पंचायत समिति (किन्हीं राज्यों में इसके नाम अलग-अलग हैं) है। इसका अधिकार क्षेत्र सामुदायिक विकास खण्ड के बराबर होता है। गुजरात, महाराष्ट्र और मैसूर में पंचायत समिति का कार्यक्षेत्र तालुके के बराबर होता है। असम और मैसूर में समिति (उक्त दोनों राज्यों में जिसे क्रमशः आञ्चलिक परिषद और तालुका विकास मण्डल कहा जाता है) के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अन्य राज्यों में उनका चुनाव परोक्ष रूप से होता है। सदस्यों में क्षेत्र की सभी पंचायतों से सरपंच, राज्य विधान सभाओं के सदस्य (जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता) और महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों एवम् सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्ञान सहयोजित (कोऑप्टेड) सदस्य शामिल हैं। महाराष्ट्र में समिति की रचना इस प्रकार होती है—जिला परिषद के स्थानीय सदस्य, पंचों द्वारा चुने गये दो

अधिनियम के अन्तर्गत कुछ पंचायतों के समूह के लिए एक अचल पंचायत (खण्ड स्तर पर की आञ्चलिक परिषद से भिन्न) चुनी जाती है। इसे कुछ न्यायिक और पुलिस सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। कुछ प्रकार के कर लगाने का भी इसे अधिकार है।

सरपंच और कुछ सहयोजित सदस्य। पंचायत के अनेक काम हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम सफाई, सड़क, लघु सिंचाई, कृषि उत्पादन, पशु-पालन, मत्स्य-पालन आदि भी शामिल हैं।

जिला परिषद की भूमिका

त्रि-सूत्री सघटन के शीर्ष पर अवस्थित है जिला परिषद। (कुछ राज्यों में इसका नामकरण भी भिन्न है।) असम के सिवाय अन्य राज्यों में इसका क्षेत्र जिले के बराबर होता है। असम में इसका गठन उप-प्रमण्डल (सब-डिवीजन) के स्तर पर होता है। अधिकांश राज्यों में जिला परिषद का चुनाव परोक्ष रूप से होता है। पंचायत समितियों के प्रतिनिधि-प्रधान-संसद और विधान सभाओं के सदस्य (बिना मताधिकार के अथवा मताधिकार सहित) तथा कुछ सहयोजित व्यक्ति जिला परिषदों के सदस्य होते हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषदों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। मद्रास और मैसूर में जिलाधीश (अथवा उप-आयुक्त) जिला विकास परिषद (यानी जिला परिषद) का अध्यक्ष होता है, जबकि आन्ध्र प्रदेश में वह जिला परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है।

जिला परिषद की भूमिका अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। महाराष्ट्र में यह पंचायत राज का आधा बिन्दु है और आयोजना व विकास विषयक सभी काम इसे सौंपे गये हैं। पर्याप्त वित्तीय स्रोत इसे दिये गये हैं और विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके अधीन हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में जिला परिषद को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यपालक काम सौंपे गये हैं। आन्ध्र प्रदेश में यह एक देख-रेख करनेवाली समन्वय-स्थापक संस्था है—हाँ, कुछ

छिट-पुट कार्यपालक कार्य भी इसे सौंपे गये हैं। शेष राज्यों में इसके कोई विशिष्ट कार्यपालक काम नहीं हैं। वहाँ यह मात्र एक देख-रेख करनेवाली तथा समन्वय-स्थापक संस्था ही है।

वास्तव में पंचायत राज की विभिन्न संस्थाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी। तथापि, इस सम्बन्ध में अग्रणी राज्यों—राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश—के अनुभवों से कुछ प्रवृत्तियों^१ दृष्टव्य हैं। पंचायत राज संस्थाओं के कार्य के रूप में सड़क बनायी गयी, कुएँ और नालियों की खुदाई की गयी, स्कूल और पुस्तकालय खोले गये तथा उर्वरक व बीजों का वितरण किया गया। सचिवालय के कागजातों से पता चलता है कि सहस्रो युवक दल, महिला मण्डल, किसान सघ, प्रतिरक्षा बैंक तथा ग्राम स्वयंसेवक सेना का काम चल रहा था। तथापि, पंचायत राज की सभी बातें ठीक से नहीं चल रही हैं। प्रायः यह शिकायत की जाती है कि इनमें से कई संस्थाएँ कोई विशेष काम नहीं कर रही हैं। ऋण, उर्वरक, बीज, साधन-सरजाम आदि के वितरण को ले कर तू-तू-मैं-मैं हुई है। महसूस किया जाता है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में पंचायत राज शायद ही कुछ हासिल कर पाया हो।

वित्तीय स्थिति

पंचायत राज संस्थाओं की कुछ असफलताओं का कारण यह ठहराया जा सकता है कि उनकी माली हालत कमजोर है। इसके लिए भी स्थानीय अधिकारियों को ही दोष का भागी बनना पड़ेगा। अधिकांश संस्थाएँ कर लगाने सम्बन्धी अपने अधिकारों का उपयोग करके पर्याप्त साधन-स्रोत जुटाने में असफल रही हैं। उदाहरण के

१ देखिये (१) ग्रामीण विकास के लिए स्वेच्छिक संस्थाओं का सहयोग, रिपोर्ट्स ऑफ दि स्टडी टीम ऑन डेमोक्रेटिक डीसेम्प्लाइजेशन इन राजस्थान १९६० और आंध्र प्रदेश (१९६१), नयी दिल्ली, (२) राजस्थान सरकार इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन दि वॉकिंग ऑफ पंचायती

राज इन राजस्थान, जयपुर, १९६१। प्राप्त सफलताओं के विस्तृत सांख्यिकीय विवरण के लिए देखिए—सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय हाय लाइट्स ऑफ दि प्रोग्राम (मोनोग्राम), नयी दिल्ली, १९६३।

लिए राजस्थान^७ में १० प्रति शत पचायत समितियों उन सभी विषयों में कर नहीं लगा सकी, जिनमें अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें कर लगाने का अधिकार है। यही बात अन्य कई राज्यों के सम्बन्ध में भी कमोबेश सही है। इसका कुछ कारण तो ग्रामीणों की सामान्य गरीबी है और कुछ कारण निर्वाचित सदस्यों को अपनी लोकप्रियता खो बैठने का डर है। पचायत राज सस्थाओं के करीब ७० प्रति शत राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विशिष्ट अनुदान से होती है। एक उत्तर-दायित्वपूर्ण स्थानीय शासन के विकास में यह एक भयंकर बाधा है, क्योंकि स्थानीय शासन की गैर वस्तुतः वित्तीय स्वायत्तता ही तो है। जिस हद तक ये सस्थाएँ आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित रहती हैं, वह यह निर्धारित करती हैं कि व्यवहार में विकेन्द्रीकरण किस सीमा तक हो सकता है। इन सस्थाओं का वित्तीय आधार मजबूत बनाने के लिए हाल ही में पचायत राज सस्थाओं के वित्त का अध्ययन करनेवाले, श्री सन्तानम कै नेतृत्व में नियुक्त, अध्ययन दल^८ ने विस्तृत सिफारिशें की हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि लाभ-दायक धंधे चलाने के लिए पचायत राज सस्थाओं को ऋण देने हेतु प्रत्येक राज में एक-एक पचायत राज वित्त निगम स्थापित किया जाय।

प्रशासनात्मक कठिनाइयाँ

सरकारी व्यक्तियों से गैर सरकारी व्यक्तियों को विकास कार्य की जिम्मेवारी के हस्तांतरण से इन दोनों के बीच प्रशासनात्मक समन्वय सम्बन्धी समस्या खड़ी हो गयी है। अभी तक उनके सम्बन्धों का निश्चित स्वरूप निर्धारित नहीं हो पाया है। रोजमर्रा के प्रशासनात्मक कामों तथा अधीनस्थ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक

कार्यवाही करने एवम् उनके स्थानांतरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों में गैर सरकारी अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने पर उनके तथा सरकारी अधिकारियों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसा देखने में आया है कि विवेकाधीन अधिकारों के सीमा निर्धारण और खण्ड की जीय के उपयोग जैसे छोटे-छोटे मामलों को लेकर खण्ड विकास अधिकारी तथा प्रधान के बीच तनाव पैदा हो जाता है। इन दोनों के बीच समरस सम्बन्ध बने रहे, इसके लिए आवश्यक है कि एक ऐसा वातावरण विकसित किया जाय जिसमें दोनों ही कार्यक्रम में एक-दूसरे के योगदान को समझे और उसकी कद्र करे। तथापि, इस बात को भी ध्यान में रखना ही चाहिये कि अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के शिक्षा स्तर में सामान्यतः व्यापक अन्तर होता है। दूसरी बात यह है कि उनके काम स्पष्ट रूप से विभक्त होने चाहिये, यद्यपि हो सकता है कि सदैव ही ऐसा करना सम्भव न हो। फिर भी, इस सम्बन्ध में स्वस्थ परम्परा विकसित करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिये। तृतीय, सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये उनकी सम्बद्ध भूमिकाओं के सम्बन्ध में समुचित समझबूझ का विकास किया जा सकता है।

निचले स्तरों पर जिम्मेवारी हस्तांतरित करने से राजनैतिक शक्ति और प्रभाव के नये केन्द्रों की स्थापना हुई है। परिणाम स्वरूप गाँवों में भी राजनैतिक गुट-बन्दी घुस बैठी है। कुछ क्षेत्रों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण फूट पैदा करनेवाला साबित हुआ है। निर्णय करने की प्रक्रिया का विश्लेषण करने से पता चलेगा कि 'सामाजिक महत्तावादी की सत्तावादी पद्धति'^९ नये-नये मार्गों से अपना दबदबा जमा रही है। जहाँ अधिकांश जनता अशिक्षित है अथवा अपने अधिकारों, प्रशासन पाली

^७ रिपोर्ट ऑन दि वर्किंग ऑफ पचायती राज इन राजस्थान, उक्त उद्धृत, पृष्ठ ८२-८३।

^८ सामुदायिक विकास, पचायती राज और सहकार मंत्रालय (भारत सरकार) रिपोर्ट ऑफ दि स्टडी टीम ऑन

पचायती राज फायनेन्स, खण्ड १ और २, नयी दिल्ली, जुलाई १९६३।

^९ एच मड्डिक डेमोक्रेसी, डीसेम्बलाइजेशन एण्ड डेवलपमेण्ट, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६३, पृष्ठ ७०।

और जनता के प्रति प्रशासक के कर्तव्यों से अनभिज्ञ हैं, वहाँ स्थानीय नियंत्रण या उत्तरदायित्व जैसे सम्बन्धों के शायद ही कुछ माने हो। अगुआई का भार वहन करने के लिए गाँवों में सगठित वर्गों अथवा नेतृत्व के अभाव में गाँव की प्रधान जाति और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न वर्ग (उदाहरणार्थ सेठ-साहूकार आदि) या अन्य कोई परम्परागत वर्ग अत्यधिक प्रभाव जमाने लगते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि राजस्थान में सामन्तों ने अपने काश्तकारों को डरा धमका कर सत्ता अपने हाथ में ले ली है। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार के उदाहरण देखने में आये हैं कि जमींदारों ने व्यापक पैमाने पर रुपये-पैसे देकर लोक-मत खरीदा है। इसी प्रकार की एक खेदजनक बात यह है कि बिहार में पचायत राज के चुनावों में जातिवाद का हाथ रहा है।

उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पचायत राज ने महान आशा का संचार करने के साथ

ही उससे भी अधिक विभ्रम पैदा कर दिया है। फिर भी, इन कमियों से किसी को भी अनावश्यक रूप से निराशावादी नहीं बन जाना चाहिये। तथापि, यह मानना बड़ा घातक सिद्ध होगा कि ग्राम समाज में जो भी दोष अथवा बुराईयों हैं, पचायत राज उनकी रामबाण औषधि है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण एक प्रक्रिया है और मात्र वाह्य अर्थात् सगठनात्मक परिवर्तनों से ही ग्रामीण जनता में जिन सामाजिक विशेषताओं तथा राजनैतिक लोकाचारों ने दीर्घ काल से घर कर रखा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ जायेगा। वास्तव में बुनियादी तौर पर पचायत राज की समस्याएँ भी वे ही हैं जो लोकतंत्र की होती हैं—निम्न आर्थिक स्तर, नागरिक जागरूकता की कमी, राजनैतिक अपरिपक्वता और नेतृत्व की अत्यधिक कमी। इन कमियों को दूर करने में ही लोकतंत्र तथा विकास की प्रेरक-शक्ति के प्रादुर्भाव की आशा निहित है।

बाल्देयर (आन्ध्र प्रदेश) २१ अप्रैल १९६४

स्नेह से लोक का उद्भव होता है। स्नेह से ही उसकी वृद्धि भी होती है। स्नेह ही शक्ति है। आनंद का मूल भी स्नेह ही है। स्नेह ही जीवन है और स्नेह-द्रोह मृत्यु है। स्नेह नरक में स्वर्ग की सृष्टि करता है। माता के हृदय में रह कर वहाँ के रक्त को दुग्ध रूपी अमृत बनानेवाला स्नेह हमें शैशव से यही संदेश देता है। इसीलिए समस्त लोक को सुना कर मैं कहना चाहता हूँ—मनुष्य मात्र एक है। उसमें कोई भी भेद नहीं है।

—भगवान बुद्ध . मझ्झिम निकाय ।

गुजरात के तीन गाँवों में ग्राम-नेतृत्व

यशवन्तासिंह जाडेजा

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के कार्यक्रम की सफलता बहुत दूर तक इस बात पर निर्भर करेगी कि गाँवों में किस किस प्रकार का नेतृत्व प्राप्य है। इस लेख में गुजरात के मगरोल खण्ड के लोहेज, दिवराणा और हुसेनाबाद गाँवों के ग्राम नेतृत्व के स्वरूप का अध्ययन करने की चेष्टा की गयी है।

चन्द ऐतिहासिक कारणों से भारतवासियों में परा-वलम्बन की भावना पनप गयी है। भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पूर्व तक यह बात बहुत कुछ अश्वमेधी थी। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने के पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस अवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीण हमेशा ही सरकार अथवा सुसम्पन्न व्यक्तियों की सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए मुँह जोहते रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीणों में अपने प्रति विश्वास पैदा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। जब तक स्वयं सेवा के प्रति यह विश्वास नहीं पैदा किया जाता, तब तक दीर्घ काल से जीवन का जो ढग उन्होंने अपना रखा है, उसमें परिवर्तन के बीज नहीं बोये जा सकते।

ग्रामीण नेतृत्व की समस्या

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भविष्य में लोगों को अपने मामलों के प्रबन्ध में सक्रिय भाग लेना भी शामिल होगा। यह महसूस किया गया कि महज ग्राम पंचायतों की स्थापना से ही वांछित सफलता नहीं मिल सकती। शक्ति तथा जिम्मेदारियों के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया गया और उससे 'पंचायत राज' का विचार सामने आया। ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त जन-प्रतिनिधियों को शामिल कर पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन किया जा रहा है। अतः पंचायत राज की सफलता बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राम

पंचायतों के जरिये किस प्रकार के नेतृत्व का विकास किया जा रहा है।

इस विकास के सन्दर्भ में ग्राम नेतृत्व की समस्या बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम नेतृत्व की वर्तमान पद्धति, उसके आधार और परिवर्तन के रुख का सविस्तार गम्भीर अध्ययन किया जाय। इस तरह के अध्ययन से हम गाँवों में नेतृत्व की जो समस्याएँ हैं, उन्हें अच्छी तरह समझ सकेंगे और नीचे से ऊपर तक सही नेतृत्व का विकास हो सकेगा।

जानकारी का संग्रह

इसी पृष्ठभूमि में इस लेख में गुजरात के मगरोल खण्ड के तीन गाँवों का पिछले दस वर्षों में ग्राम नेतृत्व के स्वरूप का अध्ययन करने तथा उसमें हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालने की कोशिश की गयी है। अध्ययन के लिए इन गाँवों को चुनने में कोई विशेष कसौटी नहीं थी। लेकिन गाँव के व्यावहारिक कार्यक्रमों के दौरान इस सम्बन्ध में चन्द प्राथमिक आकड़े प्राप्त किये गये। न तो ये आकड़े हर तरह से पूर्ण हैं और न ही यह अध्ययन किसी निश्चित सिद्धान्त पर आधारित है। यह तो चन्द तथ्यों और सांख्यिकीय आकड़ों का महज साधारणीकरण भर है और इसके पूर्ण होने का दावा नहीं किया जा सकता। तथापि, आशा की जाती है कि यह सरल आकड़ों पर आधारित मोटी रूपरेखा है, जो कि ग्राम नेतृत्व के रुख पर प्रकाश डालने में कुछ सहायक होगी।

जिन गाँवों का अध्ययन किया गया, वे हैं लोहेज, दिवराणा और हुसेनाबाद। जहाँ तक विकास गति-शीलताओं का सम्बन्ध है, उन्हें क्रमशः अच्छा, सामान्य और निम्न-स्तरीय कहा जा सकता है। उनके विषय में सामान्य जानकारी तालिका १ में दी गयी है।

हो चुका है और सभी गाँवों में चुनाव एक ही साल में सम्पन्न हुआ। इससे निर्धारित अवधि में पचायतो में हुए परिवर्तनों की तुलना करने का अवसर मिलेगा। सर्व प्रथम मतदाता सूची पर जातिगत वगणितानुसार ध्यान देना आवश्यक होगा। सिर्फ बड़े वर्गों को ही

तालिका १
गाँवों का सामान्य परिचय

	लोहेज	दिवराणा	हुसेनाबाद
आबादी	२,५००	१,२५०	५५०
पचायत की स्थापना का वर्ष	१९५२	१,९५५	१९५२
अब तक कितनी बार पचायतो के चुनाव हुए	४	३	४
प्रत्येक बार गठित पचायत के सदस्यों की संख्या			
१९५२ में	११	—	१३
१९५५ में	११	९	१३
१९५८ में	१३	९	१३
१९६२ में	९	७	७

तालिका २
तीनों गाँवों में मतदाताओं की सघटना

	लोहेज		दिवराणा		हुसेनाबाद
अहीर	४७५				
हरिजन	८७	कुणबी	३१६	घाची	१११
राजपूत	७०				
शेख	५७	कोली	८०	अहीर	४८
रैबारी	५०	हरिजन	२०		
ब्राह्मण	२८	कुम्हार	१४	कोली	३१
बनिया	२४	ब्राह्मण	१२		
बावा	२२	लोढ़ाणा	१०	कुम्हार	२०
कुम्हार	१७	भावा	१०		
बैरठ	१७	मुसलमान	१०	हरिजन	१८
दर्जी	१६				
अन्य	४१	अन्य	२४	अन्य	१४
कुल	९०४		४९६		२४२

आबादी के हिसाब से ये गाँव विभिन्न श्रेणियों में आते हैं और वहाँ ग्राम पचायतों में भी काफी समय से काम कर रही हैं। सभी गाँवों में पचायतों का चुनाव ३ से ४ बार

विशिष्ट उप-जातियों में विभाजित किया गया है, जबकि छोटे वर्गों को 'अन्य' कह कर सम्बोधित किया गया है। यद्यपि इन छोटे वर्गों को कम आबादी होने के नाते 'अन्य'

की उपाधि दी गयी है, तथापि उन्हें बिल्कुल बेकार नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ग्राम नेतृत्व के विकास में उनका भी हाथ है। इन तीनों गाँवों में जातिवार मत-दाताओं की सूची उपर तालिका २ में दी गयी है।

तालिका २ से यह स्पष्ट है कि लोहेज, दिवराणा और हुसेनाबाद में क्रमशः अहीर, कुणबी और घाची उप-जातियों की प्रमुखता है। यदि जात्यनुसार सख्या के हिसाब से देखें तो ग्राम-नेतृत्व उक्त गाँवों में इन जातियों के हाथ में चला गया होता। तथापि, तथ्यो

कि प्रारम्भिक अवस्था में चुने गये नेता ऊँची जातियों के थे। (देखिये तालिका ३।) परन्तु बाद में नेतृत्व धीरे-धीरे तीनों ही गाँवों में उपर्युक्त दलों के हाथ में आ गया।

नये नेतृत्व का प्रादुर्भाव

इस झुकाव का कारण लोगों का जातिवादी दृष्टिकोण है। प्रारम्भ में नेतागण ऊँची जातियों से आये, भले ही उनकी आबादी कितनी ही कम क्यों न हो।

तालिका ३

ग्राम नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी

	नाम	जाति	उम्र	शैक्षणिक योग्यता
लोहेज				
१९५२	सरपच	नानालाल हसरान	बनिया	४८ वनकुलर ५
	उप सरपच	मणिलाल नागजी	ब्राह्मण	३८ वनकुलर ६
१९५५ } १९५८ } १९६२ }	सरपच	अर्जन बेजा	अहीर	२१ वनकुलर ६
	उप सरपच	रामभाई जीना	अहीर	२१ वनकुलर ६
दिवराणा				
१९५५ } १९५८ } १९६२ }	सरपच	लक्ष्मण कचरा	कुणबी	४८ वनकुलर ४
१९५५	उप सरपच	जारजी नारण	कुणबी	४५ वनकुलर ४
१९५८	" "	मेजी देवा	कुणबी	४० अशिक्षित
१९६२	" "	मोहन लक्ष्मण	कुणबी	३० वनकुलर ४
हुसेनाबाद				
१९५२	सरपच	वजूभाई शाह	बनिया	४६
	उप सरपच	अमुभाई शाह	बनिया	४३
१९५५	सरपच	काला जेसा	अहीर	४७ वनकुलर १
	उप सरपच	ईसा कासम	घाची	३५ वनकुलर ७
१९५८	सरपच	ईसा सुलेमान	घाची	३० वनकुलर २
१९६२	उप सरपच	अलसी घाना	अहीर	४० अशिक्षित

और इकट्ठी की गयी जानकारी पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में तीन में से दो गाँवों में जो सरपच और उप सरपच चुने गये, वे उन जातियों के थे, जिनकी सख्या कम थी। एक यह भी तथ्य सामने आया

वे जन-मानस तैयार करनेवाले पारम्परिक नेता थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया और निम्न जातियों वाले दल पचायत के संगठन तथा गाँव के प्रशासन में अपने अधिकार एवम् कर्तव्य के प्रति सजग होते गये,

ऊँची जातियों का स्वार्थमय प्रारम्भिक नेतृत्व समाप्त होता गया।

१९५८ में यह उम्र ३० और ४० वर्ष के बीच रही और वे ही व्यक्ति फिर १९६२ में भी चुने गये।

आयु-वर्ग की ओर देखने से यह पता चलता है कि लोहेज गाँव में सरपच और उप सरपच की उम्र क्रमशः ४८ और ३८ वर्ष थी। परन्तु बाद में नेतृत्व २१ वर्षीय युवकों को सौंपा गया और वे आज तक उस पद पर आसीन हैं। दिवराणा में श्री लक्ष्मण कचरा १९५५ में ४८ वर्ष की उम्र में सरपच चुने गये और तब से आज तक कोई नया सरपच नहीं हुआ। लेकिन उप सरपच के मामले में प्रत्येक चुनाव में नया व्यक्ति चुना गया है।

शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता के विषय में हम यह पाते हैं कि नेतृत्व में परिवर्तन के लिए यह पहलू जिम्मेदार नहीं रहा है। वस्तुतः कई सरपच तो पिछले सरपच से कम पढ़े-लिखे भी पाये गये हैं। अतः नेतृत्व में परिवर्तन तथा शैक्षणिक योग्यता के बीच कोई प्रत्यक्ष विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है। इस बात की व्याख्या तो सभवतः ग्रामीण मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके

तालिका ४

नेताओं के व्यवसाय

लोहेज				
१९५२	नानालाल हसराम	(बनिया)	सरपच	व्यापारी
	मणिलाल नागजी	(ब्राह्मण)	उप सरपच	व्यापारी
१९५५ } १९५८ } १९६२ }	अर्जन वेजा	(अहीर)	सरपच	किसान
	रामभाई जीना	(अहीर)	उप सरपच	किसान
दिवराणा				
१९५५ } १९५८ } १९६२ }	लक्ष्मण कचरा	(कुणबी)	सरपच	किसान और व्यापारी
	सभी उप सरपच			किसान
हुसेनाबाद				
१९५२	वजुभाई शाह	(बनिया)	सरपच	ठेकेदार
	अमृभाई शाह	(अहीर)	उप सरपच	ठेकेदार के सहायक
१९५५	काला जेसा	(अहीर)	सरपच	किसान
	ईसा कासम	(घाची)	उप सरपच	किसान
१९५८	ईसा सुलेमान	(घाची)	सरपच	किसान
	अलसी घाना	(अहीर)	उप सरपच	किसान

तीनों चुनावों में चुने गये उप सरपचों की आयु क्रमशः ४५, ४० और ३० वर्ष थी। अतः नेतृत्व अधिक उम्र वाले के हाथ से निकल कर धीरे-धीरे कम उम्र के लोगों के हाथों में आता गया। हुसेनाबाद के मामले में भी सरपचों और उप सरपचों की उम्र १९५२ में ४३ और ४६ तथा १९५५ में ३५ से ४७ वर्ष के बीच रही। सब

ही की जा सकती है। सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम प्रशासन में उच्च शैक्षणिक योग्यता की बनिस्बत जरूरत है अनुभवजन्य प्रखर सामान्य ज्ञान और प्रगाढ़ अनुभूति की।

नेतृत्व का घघे के साथ सम्बन्ध के मामले में हम यह पाते हैं कि सभी गाँवों में प्रथम चुनाव में सरपच के लिए

व्यापारियों को चुना गया। सम्भवतः उन्होंने महाजनो भूमि सुधार के फलस्वरूप जमीन के मालिक बन गये का कार्य किया और परम्परागत जमींदारों अथवा जागीर- और जिन्हे अपनी बहु-संख्यक जाति का अधिक समर्थन दारों के अभाव में सभी गाँवों में वे स्वार्थी तत्वों का प्राप्त हुआ। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि प्रतिनिधित्व करनेवाले एक मात्र व्यापारिक वर्ग बन नेतृत्व धीरे-धीरे व्यापारियों के हाथ से निकल कर

तालिका ५

विभिन्न जाति समूहों का प्रतिनिधित्व

श्रेणी	पंचायतों में जात समूहों का प्रतिनिधित्व	१९५२ में पंचायत के सदस्यों की संख्या (सभी गाँव)	१९५२ में कुल सदस्यों का प्रतिशत (सभी गाँव)	१९५५ में पंचायतों के सदस्यों की संख्या (सभी गाँव)	१९५५ में कुल सदस्यों का प्रतिशत (सभी गाँव)	१९५८ में पंचायतों के सदस्यों की संख्या (सभी गाँव)	१९५८ में कुल सदस्यों का प्रतिशत (सभी गाँव)	१९६२ में पंचायतों के सदस्यों की संख्या (सभी गाँव)	१९६२ में कुल सदस्यों का प्रतिशत (सभी गाँव)
सर्वोच्च वर्ग	ब्राह्मण	२	२९.२	२	१२.१	१	८.६	१	१३
	राजपूत	१		—		१		१	
	बनिया	४		२		१		१	
	योग	७		४		३		३	
उच्च वर्ग	बावा	१	१२.५	१	६.२	—	५.७	—	४.३
	सुतार	१		१		१		१	
	कुम्हार	१		—		१		१	
	योग	३		२		२		२	
निम्न वर्ग	अ हिन्दू								
	अहीर	५	५०.०	८	६९.७	६	७१.५	६	७४.००
	कृषबी	—		४		६		४	
	कोली	२		४		१		२	
	रैबारी	१		२		२		१	
	आ मुसलमान	४		५		१०		४	
	योग	१२		२३		२५		१७	
निम्नतम वर्ग	हरिजन	२	८.३	४	१२.१	५	१४.२	२	८.७
	कुल योग	२४	१००	३३	१००	३५	१००	२४	१००

गये। (देखिये तालिका ४) परन्तु बाद में यह देखा गया कि जिन व्यापारियों को कृषि कार्य का अतिरिक्त सहारा नहीं था उन्हें उन व्यक्तियों ने उखाड़ फेंका, जो कि किसानों के हाथों में चला गया है। यदि हम सम्पूर्ण पंचायत की दृष्टि से नेतृत्व के प्रश्न पर विचार करें तो हमें इसके गठन तथा पिछले दस वर्षों

मे इसमे हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना होगा। इन गाँवों में भी अधिक सख्या किसानों की ही है। अतः पचायत में उन्हें अधिक स्थान मिला। लेकिन यदि हम दस वर्ष की अवधि में प्रतिनिधित्व के प्रातिशत्य को प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत के आधार पर देखे तो पाते हैं कि प्रारम्भ में किसानों का प्रतिनिधित्व कम था और ऊँची जातियों का अधिक। (देखिए तालिका ५।)

जातियों की तुलनात्मक अवस्था

ब्राह्मण, राजपूत और बनियो को, जोकि ऊँची जात में गिने जाते हैं, सन् १९५२ में २९ २ प्रति शत स्थान मिले (तीनों पचायतों के कुल स्थानों में से)। फिर १९५५ और १९५८ में उनका प्रातिशत्य कम होता गया और अन्ततः १९६२ में सिर्फ १३ प्रति शत रह गया।

बावा, सुतार और कुम्हारों का स्थान दूसरे दर्जे में है। सन् १९५२ में पचायतों में उनका प्रातिशत्य १२ ५ था, जोकि बाद में बहुत ही कम हो गया। सन् १९५५, १९५८ और १९६२ में उनका प्रातिशत्य क्रमशः ६ २, ५ ७ और ४ ३ हो गया।

निम्न श्रेणी में आते हैं कुणबी, अहीर, कोली और रैबारी। (उनमें से अधिकांश किसान हैं—रैबारी भी, जोकि चरवाहे भी हैं।) इस श्रेणी में मुसलमान भी शामिल हैं, जोकि खेती करते हैं। सन् १९५२ में उनका प्रतिनिधित्व ५० प्रति शत था, जो धीरे-धीरे बढ़ कर १९५५ में ६९ ७, १९५८ में ७१ ५ और १९६२ में ७४ प्रति हो गया।

और, अन्त में आते हैं हरिजन, जोकि अछूत समझे जाते थे और आज भी निम्नतम श्रेणी में गिने जाते हैं। तीनों ही पचायतों में उनका प्रतिनिधित्व हुआ और उनका प्रातिशत्य बहुत-कुछ बराबर ही रहा है, क्योंकि उनके लिए निश्चित स्थान सुरक्षित हैं। उनका प्रतिनिधित्व १९५२ में ८ ३ प्रति शत था, १९५५ और १९५८ में इसमें थोड़ी घट-बढ़ हुई और पुनः १९६२ में यह

८ ७ प्रति शत हो गया।

इन गाँवों के राजस्व खाते से जो आकड़े प्राप्त किये गये हैं, उनसे एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिली है कि बड़े भूस्वामियों का प्रतिनिधित्व प्रारम्भ में बहुत कम था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, सभी पचायतों में बड़े भूस्वामियों की सख्या बढ़ती गयी। सभी पचायतों में भूस्वामी वर्ग का, जिनमें २५ बड़े भूस्वामी आते हैं, प्रतिनिधित्व १९५२ के २० ८ प्रति शत से धीरे-धीरे बढ़ कर १९६२ में ६५ २ हो गया। अलग-अलग गाँवों में भी यह प्रवृत्ति है। लोहेज में यह प्रातिशत्य १९५२ के ९ १ से बढ़ कर १९६२ में ६६ ६ हो गया। दिवराणा में भी यह १९५५ के ४४ ४ प्रति शत से बढ़ कर १९६२ में ५७ १ हो गया, जबकि हुसेनाबाद में १९५२ के ३० ७ प्रति शत से बढ़ कर १९६२ में ७१ ४ तक पहुँच गया। इसमें धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। इस प्रकार पचायतों में अपनी बड़ी सख्या के बल पर न सिर्फ किसान प्रवेश पाते जा रहे हैं, लेकिन उनमें से भी अधिकांश स्थानों पर बड़े भूस्वामियों का अधिकार है।

युवक और अनुभव

यदि हम सभी गाँवों की पचायतों के सदस्यों का आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकरण करें तो पाते हैं कि प्रारम्भ में अधिकांश सदस्य मध्यम आयु वर्ग—३१ से ४० वर्ष और ४१ से ५० वर्ष—के थे (देखिए तालिका ६)। सन् १९५२ में ७९ प्रति शत सदस्य इन्हीं आयु-वर्गों से थे, जबकि १९५५ में इन वर्गों के सदस्यों का प्रातिशत्य ७३ था। सन् १९५८ और १९६२ में सभी वर्गों को करीब-करीब समान प्रतिनिधित्व मिला। इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि २१ से ३० वर्ष और ५१ से ६० वर्ष दोनों ही वर्गों के सदस्यों को ग्राम्य प्रशासन कार्य में लाया गया। जिन लोगों को पहले पचायतों में मध्यम वर्ग के लोगों के साथ जिम्मेदारियाँ वहन करने में कच्ची उम्र का (युवक) अथवा अधिक बूढ़ा समझा जाता था, वे अब अपना उचित स्थान प्राप्त कर रहे हैं। ये वर्ग

पचायतो को सक्रिय बनायेगे तथा अनुभव भी प्रदान करेगे।

तालिका ६

विभिन्न आयु वर्गों में आनेवाले पचायत सदस्यों की संख्या

	१९५२	१९५५	१९५८	१९६२
२१ से ३०	२	५	१०	५
३१ से ४०	१०	११	९	५
४१ से ५०	९	१३	८	५
५१ से ६०	३	३	८	६
६१ से ७०	०	१	०	२
योग	२४	३३	३५	२३

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्राम स्तर पर नेतृत्व पद्धति में चन्द महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आते हैं। यद्यपि इन परिवर्तनों के निश्चित रुख को बताना कठिन होगा, तथापि ग्राम नेतृत्व के परिवर्तन की प्रक्रिया की मुख्य-मुख्य बातों को बताना असम्भव नहीं होगा। इन्हे संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है

(१) ऊँची जात के आधार पर नेतृत्व की प्राप्तिवाली अवस्था में परिवर्तन होता जा रहा है, (२) नेतृत्व के लिए मुख्य आधार अधिक आबादी बन गयी है, (३) नेतृत्व युवकों के हाथ में आता जा रहा है, (४) शैक्षणिक योग्यता के बदले ग्राम सम्बन्धी अनुभव और समझ का अधिक महत्व है, (५) जो लोग खेती नहीं करते वे किसानों को नेतृत्व का भार सौंपते जा रहे हैं, (६) सभी आयु वर्ग वाले नेतृत्व के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं, (७) बड़े भूस्वामी ग्राम नेतृत्व पर एकाधिकार करने के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, (८) विशेष प्रतिनिधित्व भी समाज के निम्नतम वर्ग (हरिजन) को नेतृत्व के निकट नहीं पहुँचा सका है।

संक्षेप में ग्राम स्तर पर नेतृत्व के मामले में हो रहे परिवर्तनों की यह मुख्य रूझान है। बहुत सम्भव है कि चन्द गाँवों में ये सभी प्रवृत्तियाँ पायी जाये तथा कुछ सभी गाँवों में। तथापि, पचायत राज की एक स्थायी और महत्वपूर्ण संस्था के सन्दर्भ में ग्राम नेतृत्व के भावी विकास की दृष्टि से हर रूख का बड़ा महत्व है।

जूनागढ़ १४ मार्च १९६४

खादी ग्रामोद्योग का एकादश वर्षाभ्यन्त एक सितम्बर के अन्त में प्रकाशित होगा। लेखकों से अनुरोध है कि वे अपने लेख सम्पादक के पास अगस्त १९६४ के प्रथम सप्ताह तक भेज दें।

मिट्टी की अभिघट्यता और अपारदर्शी काचन : चन्द प्रयोग

जागेद्वर गो. श्रीखण्डे और यशवन्त बि. खेर

इस लेख में मिट्टी की अभिघट्यता का परीक्षण करने तथा टिन आक्साइड के बदले जिरकोनियम आक्साइड का उपयोग कर वर्तमान अपारदर्शी काचन को सस्ता बनाने हेतु किये गये प्रयोगों के परिणामों का विवरण दिया गया है।

अभिघट्यता (प्लास्टिसिटी) परीक्षण इस सिद्धान्त पर आधारित है अभिघट्य (प्लास्टिक) मिट्टी में विभिन्न अनुपात में प्राकारिक और अप्राकारिक दोनों ही प्रकार के लसदार पदार्थ रहते हैं। मिट्टी जितनी ही अभिघट्य होगी, पलस्तर साचे में प्रचूषण उतना ही कम होगा और विपरीतावस्था में प्रचूषण उतना ही अधिक होगा।

मिट्टी के अभिघट्यता परीक्षण में समान घनत्व और मोटाई के पलस्तर साचे उपयोग में लाये जाते हैं। पलस्तर और पानी का अनुपात होता है—५० तोला पानी में १०० तोला पलस्तर, यह प्याले के सिर्फ एक ही साचे के लिए पर्याप्त होता है और ऐसे ६ साचों का उपयोग किया जाता है।

प्रक्रिया

परीक्षण की जानेवाली मिट्टी को प्रथम जल की आवश्यक मात्रा में मिलाते हैं तथा ककड़ों और अन्य पदार्थों से उसे मुक्त करने के लिए १५० तार की चलनी में छानते हैं। फिर छानी गयी मिट्टी को बैठने देते हैं और प्लावी जल को निथार कर निकाल देते हैं। तब शेष मिट्टी को पूर्णतः सूख जाने देते हैं। अब इस मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को अलग-अलग बर्तन में पानी में मिलाते हैं और फिर तैयार चिकनी मिट्टी को १५० तार की चलनी में छानते हैं तथा प्रत्येक प्रकार की चिकनी मिट्टी के घनत्व को ४५ डिग्री सान्द्र-द्रवमापी पर रखते हैं। चिकनी मिट्टी को साचे में डालते

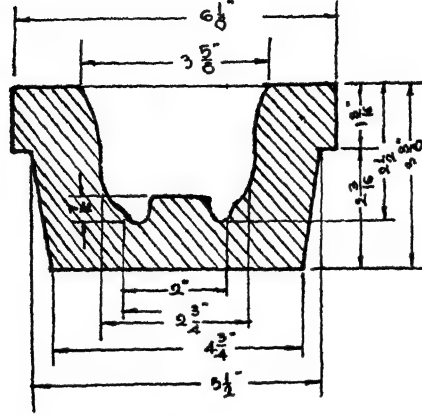
हैं, स्तरे को बराबर रखते हैं और साचे में दस मिनट रगते हैं। फिर चिकनी मिट्टी को साचे से बाहर उड़ेल देते हैं। साँचे में रह गयी मिट्टी की परत को सूखने देते हैं और फिर उसे निकाल कर बिल्कुल सूखने देते हैं। हर साचे से निकले सूखे हिस्से का वजन लेते हैं। अभिघट्यता को सूखी वस्तु का वजन लेकर तथा उस वस्तु को काट उसकी मोटाई नाप कर माप सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कई किस्म की मिट्टी के हमारे परीक्षणों के परिणाम निम्न तालिका में दिये गये हैं

मिट्टी परीक्षण के परिणाम

मिट्टी का नाम	प्रचूषित सूखी मिट्टी का वजन (तोला)	विशेष
माण्डक लाल मिट्टी	४ $\frac{3}{4}$	बहुत ही अभिघट्य
सलोद कपासी मिट्टी	५ $\frac{1}{2}$	"
बडगौव लाल मिट्टी	५ $\frac{3}{4}$	"
माहेगौव लाल मिट्टी	५ $\frac{3}{4}$	"
कोठारी सफेद मिट्टी	५ $\frac{1}{2}$	"
पावनार मिट्टी	९ $\frac{3}{4}$	अभिघट्य
घान मिट्टी	७ $\frac{1}{2}$	अर्ध-अभिघट्य
जबलपुर मिट्टी	७ $\frac{1}{2}$	अर्ध-अभिघट्य
बल्लारपुर मिट्टी	८ $\frac{1}{2}$	बहुत ही कम अभिघट्य
माण्डक चीनी मिट्टी	८ $\frac{3}{4}$	"
बम्बई चीनी मिट्टी	६ $\frac{1}{2}$	अर्ध-अभिघट्य

उपर्युक्त परिणाम तीन परीक्षणों के मध्यमाक है, जोकि सदृश्य परिणाम दशति है।

साचे के आकार और माप से सम्बन्धित चित्र नीचे दिया गया है।



कप का पलस्त्ररी सॉंचा

टीन आक्साइड के बदले जिरकोनियम आक्साइड का उपयोग कर वर्तमान अपारदर्शी काचन को सस्ता बनाने के लिए किये गये प्रयोग : परीक्षण १०५० डिग्री

सेटीग्रेड पर किये गये और निम्न तीन कार्यकारी सघटन उपयोगी पाये गये

काचन सघटन 'इ' में उतनी सफेदी नहीं मिली, जितनी कि काचन 'अ' और 'आ' में प्राप्त हुई। सघटन 'अ' और 'आ' लाल मिट्टी के बर्तनों पर अधिक अच्छे लगे। टीन आक्साइड की मौजूदा कीमत को ध्यान में रख कर तथा इसे सिर्फ अपारदर्शी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हुए वर्तमान काचन की कीमत करीब १ रुपया ३७ नये पैसे पौण्ड पड़ेगी।

अपारदर्शक बनाने के लिए जिरकोनियम आक्साइड के साथ एक से डेढ़ प्रति शत टीन आक्साइड का उपयोग करने से काचन खर्च प्रति पौण्ड करीब ८० नये पैसे कम हो जायेगा। यदि कच्चा माल अधिक मात्रा में खरीदा जाय तो खर्च और भी कम पड़ेगा। इस बात के लिए परीक्षण अभी जारी है कि टीन आक्साइड का इस्तेमाल बिल्कुल ही न करना पड़े और साथ ही अच्छा अपारदर्शी काचन भी हो।

कार्यकारी सघटन

नाम	सीसाविहीन काचन		सीसा काचन
	अ	आ	इ
काच चूर्ण	२९ ८०	२९ ८०	३० ७३
सुहागी फिट	२९ ८०	२९ ८०	० ००
चीनी मिट्टी	७ ७५	७ ७५	८ ००
फेल्सपार	५ १०	६ १२	५ २६
शकमक	६ १२	६ १२	६ ३३
'बाल' मिट्टी	४ ०८	५ १०	४ ७५
जिन्कोक्साइड	६ १२	५ ७१	४ ७५
जिरकोनियम आक्साइड	१० २०	८ १७	९ ४५
टीन आक्साइड	१ ०३	१ ४३	० ००
सफेद सीसा	० ००	० ००	३० ७३
	११०.००	१०० ००	१०० ००

अन्नोपभोग और बढ़िया से बढ़िया अनाज की ओर : एक अध्ययन

तण्डलम सो. यशवंत और रा. राजगोपालन

साधारण अन्नोपभोग और विशेष रूप से उत्तम अन्नोपभोग के साथ ही जाति, आय और व्यावसायिक स्तरों पर अन्नोपभोग के अध्ययनार्थ आकड़े एकत्रित करने हेतु मद्रास राज्य के उप्पातुर गांव में बेच-मार्क सर्वेक्षण किया गया। इस लेख में उसी का विश्लेषण प्रस्तुत है।

इस लेख के दो उद्देश्य हैं (१) उपभोग स्तर का परीक्षण करना, और (२) बढ़िया अनाज के उपभोग-अनुपात की भिन्नता का अध्ययन करना। इनका अध्ययन (अ) जाति, (आ) धंधा, और (इ) आय के सन्दर्भ में किया गया है।

इस कार्य के लिए मद्रास राज्य में रामनाथपुरम जिले का उप्पातुर गाँव चुना गया, जोकि शुष्क क्षेत्र है। मद्रास विश्वविद्यालय के कृषि-अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र द्वारा १९५८ में सम्पन्न बेच-मार्क सर्वेक्षण के जरिये आकड़े संग्रहीत किये गये। बेच-मार्क सर्वेक्षण के एक अंग रूप सभी घरों से सर्वेक्षण काल के एक माह पूर्व के उपभोग आकड़े इकट्ठे किये गये।

अर्थ-व्यवस्था की मुख्य बातें

उप्पातुर गाँव में २,१२० लोग ४९३ परिवारों में बसते हैं। गाँव में बसनेवाली मुख्य जातियाँ हैं नैकर, यादव और हरिजन, जिनमें ईसाई भी शामिल हैं। शुष्क गाँव होने के कारण यहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक है। खेतिहरो में जमीन की मालिकी के मामले में बड़ी भिन्नता है। मुख्य फसलों के रूप में कपास, धनिया, लाल मिर्च, कुम्बू, कडीरैवली और प्याज हैं। कुल ४,६६४ एकड़ जमीन में से सिर्फ २० एकड़ में ही धान की खेती होती

है। गाँव में चावल बाहर से मगाया जाता है। कुम्बू के मामले में भी, जोकि गाँव का प्रमुख अनाज है, कुल का सिर्फ ५६ प्रतिशत ही बेचा जाता है। व्यापारियों द्वारा प्रदत्त आकड़े यह दर्शाते हैं कि गाँव में बाजरा भी बाहर से मगाया जाता है। इसकी पुष्टि इससे की जा सकती है कि अनाज की खपत कुल उत्पादन से अधिक है।

सिर्फ चावल खानेवाले २९ परिवारों तथा बाजरा खानेवाले चार परिवारों को छोड़ कर बाकी परिवार चावल और बाजरा दोनों ही अनाज खाते हैं।

जाति और अनाज का उपभोग

गाँव में १७ जातियाँ हैं। इस विश्लेषण के लिए पारम्परिक रूप से निर्धारित समान सामाजिक और व्यावसायिक हिसाब रखनेवाली जातियों को एक में शामिल कर दिया गया है। नैकर, नाडार और यादव जैसी मुख्य जातियों को अलग ही रखा गया है। होटल में भोजन करनेवाले १२ एक-सदस्यीय परिवारों को इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न जातियों में प्रति वयस्क प्रति दिन अनाज की खपत यानी अन्नोपभोग का विवरण तालिका १ में दिया गया है।

तालिका १

विभिन्न जातियों में प्रति वयस्क प्रति दिन
अनाज की खपत

जाति	प्रति वयस्क प्रति दिन अनाज खपत (औंस में)*
नैकर	३४ ४६
नाडार	२४. ३७
यादव	२९ १५
मजदूर†	२७ ३७
दस्तकारियों और मवा ‡	२२ ०३
अन्य‡ (उन्नत जातियाँ)	२९ ५९
गाँव के लिए औसत	२८ ५३

* वयस्क इकाई 'लस्क कोपफिसिण्ट' के आधार पर निकाली गयी है।

§ मजदूरों में पारायण, चक्कीलियों, ईसाई और तेवर शामिल हैं।

† इसमें असारी, बन्नत, अम्बत्तन, दर्जी, पडरम् और बेतुवन शामिल हैं।

‡ इसमें ब्राह्मण, चेट्टियार, पिळ्ळै और मुदालियर शामिल हैं।

गाँव में प्रति वयस्क प्रति दिन अनाज की खपत प्रचलित स्तर से काफी ऊँची है। यह इस कारण हो सकता है कि (अ) परिवारों की, खास कर किसानों की, जो खपत बतायी गयी है, उसमें आकस्मिक श्रमिकों को दी जानेवाली दस्तूरी भी शामिल हो, और (आ) कुम्बु तथा कुडी-रैवली जैसे घटिया अनाजों के मामले में जो खपत बतायी गयी है, उसमें भूसी का वजन भी शामिल हो।

मजदूरी भुगतान और मजदूरी प्राप्ति से सम्बन्धित आकड़े दर्शाते हैं कि जो दस्तूरी दी जाती है, वह आकस्मिक श्रमिकों को दी जानेवाली मजदूरी के अनुपात से बहुत कम है। पर्यवेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि कुडीरैवली और कुम्बु जैसे अनाजों के मामले में बर्बादी अधिक हुई है। इस बर्बादी को बाद देने पर भी यह खपत बहुत अधिक लगती है।

विभिन्न जाति दलों के बीच सबसे अधिक भिन्नता नैकर जाति और सेवक जाति के बीच है। गाँव की अधिकांश भूमि नैकरो की है। कुल १३५ में से १०६ नैकर परिवार तो मुख्यतः कृषक हैं। कृषक बन्नतो, अम्बत्तनो और चक्कीलियानो को भोजन देते हैं। इस कारण खपत बहुत अधिक है। सेवक जाति दल को दस्तूरी मिलती है। अतः उनके सम्बन्ध में बतायी गयी खपत बहुत कम है। यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाय तो विभिन्न जाति दलों के बीच खपत के स्तर में बहुत थोड़ी भिन्नता होती है।

आय स्तर और खपत

यह जानने का भी प्रयास किया गया है कि एक ही जाति के अन्दर क्या आय-स्तर की भिन्नता के कारण अनाज की खपत के स्तर में भी भिन्नता आती है? इस कार्य के लिए प्रत्येक जाति में विभिन्न आय-स्तरों पर प्रति वयस्क जो खपत बतायी गयी है, उसका विचरण गुणाक जोड़ा गया। परिणाम तालिका २ में दिखाये गये हैं। यादव जाति में भिन्नता सबसे अधिक है, जबकि श्रमिक और सेवक जाति में सबसे कम। श्रमिक और सेवक जाति दलों के परिवारों के आय-स्तर का निकट-परीक्षण करने से यह ज्ञात हुआ कि आय में वृद्धि होने के साथ-साथ परिवार का औसत आकार भी बढ़ा। इससे विभिन्न परिवारों के बीच प्रति वयस्क उपभोग में प्राप्त अन्तर कम हो गया।

तालिका २

प्रत्येक जाति में विभिन्न आय स्तरों के लोगों में
प्रति वयस्क प्रति दिन अन्नोपभोग का विचरण गुणाक

जाति	विचरण गुणाक
नैकर	१३ ८७ प्रति शत
नाडार	१९ २३ " "
यादव	२६ ०० " "
श्रमिक	७ ६६ " "
सेवाएँ	६ ८४ " "
अन्य	१५ ५० " "

यादवों में यदि तीन घरों में इतनी अधिक खपत न हुई होती तो विचरण गुणांक इतना अधिक नहीं होता।

धंधा और अन्नोपभोग

धंधे के सन्दर्भ में अनाज की खपत के अध्ययन के लिए सभी पेशेवर जातियों को दो किस्म के श्रमिक वर्गों में विभक्त करना उपयोगी होगा— अधिक खपत दर्शानेवाले और कम खपत दर्शानेवाले। इसलिए व्यावसायिक दलों को इन दो श्रेणियों में रखा गया है। प्रति वयस्क खपत से सम्बन्धित आकड़े तालिका ३ में दिये गये हैं।

तालिका ३

विभिन्न धंधों में प्रति वयस्क प्रति दिन अन्नोपभोग

व्यावसायिक दल	अन्नोपभोग (औंस में)
अ मजदूर	
१ श्रमिक	२७ ८८
२ परमावश्यक सेवाएँ	१७ २०
३ कला और दस्तकारियों	२१ ३४
४ छोटे भूस्वामी §	२६ ४६
५ मध्यम भूस्वामी †	३६ ५३
६ * बड़े भूस्वामी ‡	३६ १८
आ अन्य	
१ व्यापार	२३ २२
२ पेशेवर	२१ ७०

* पर्यवेक्षण करनेवाले तथा शारीरिक श्रम करनेवाले श्रमिकों को वर्गीकृत करने की कोशिश नहीं की गयी है। पर्यवेक्षण से यह पता लगा है कि कई बड़े भूस्वामी भी शारीरिक श्रम करते हैं।

§ १० एकड़ से कम भूमि के स्वामी।

† १० से २५ एकड़ तक के बीच के भूस्वामी।

‡ २५ एकड़ तथा उससे अधिक के भूस्वामी

परिवारों की खपत में परमावश्यक सेवाओं और दस्तकारियों के लिए, खास कर चमारों को, दी गयी दस्तूरी शामिल है। दी गयी दस्तूरी का विस्तृत विवरण आकड़ों में नहीं है। फिर, कुल खपत में दस्तूरी का क्या अनुपात है, यह भी बताना सम्भव नहीं है। बड़े और मध्यम भूस्वामियों के लिए यह अनुपात काफी बड़ा है। बड़े भूस्वामी परिवारों में अधिक खपत के लिए एक कारण यह भी है कि वे खेतों के लिए स्थायी नौकर रखते हैं। आम तौर पर यह पाया जाता है कि खेत में काम करनेवाले नौकर दूसरों से अधिक खाते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए जिन परिवारों में स्थायी कृषि नौकर हैं, उन्हें दूसरे परिवारों में अलग रखा जा है।

इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए प्रति वयस्क औसत उपभोग नीचे दिखाया गया है

श्रेणी	दैनिक अन्नोपभोग (औंस में)
स्थायी कृषि सेवक रखनेवाले	३६ ५०
स्थायी कृषि सेवक न रखनेवाले	३५ ८०

यह देखा गया है कि स्थायी कृषि सेवक रखनेवालों की खपत कुछ अधिक है। श्रमजीवि दल में कम खपत परमावश्यक सेवाओं, कला और दस्तकारियों में है। उनकी प्रति व्यक्ति आय भी गाँव में सबसे कम है। श्रमजीवि परिवारों तथा दूसरों के बीच प्रति वयस्क खपत में बड़ी भिन्नता है। व्यापारी और पेशेवर श्रेणियों अनाज कम खाती हैं। उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि पेशे का स्वरूप कुल अनाज की खपत पर प्रभाव डालता है।

प्रत्येक धंधे के अन्तर्गत अनाज की खपत पर आय के प्रभाव का भी परीक्षण किया गया है। प्रत्येक पेशेवर श्रेणी के लिए जोड़ा गया विचरण गुणांक तालिका ४ में दिया गया है।

तालिका ४

विभिन्न धधो में आय स्तर के आधार पर प्रति वयस्क
प्रति दिन अनाज खपत का विचरण गुणांक

धधा	विचरण गुणांक (प्रातिशत्य)
बड़े भूस्वामी	९ ४०
मध्यम भूस्वामी	१६ ४७
छोटे भूस्वामी	१५ ३२
कला और दस्तकारी	६ ८६
श्रम	९ ०३
परमावश्यक सेवाएँ	२५ ९३
व्यापार	२१ ३७
पेशेवर	१६ ८७

जाता है। इन धधो से उपहार के तौर पर प्राप्त तैयार भोजन का विवरण नहीं मिला है। इसके कारण विचरण बहुत बढ जाता है। यदि इस श्रेणी को नजरअन्दाज कर दिया जाय तो इसके व्यापारी वर्ग में विचरण अधिक पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जाति के अन्दर आय का जितना प्रभाव पडता है, धधे के अन्दर उससे कम पडता है।

प्रत्येक धधे के लिए आय के अनुसार श्रेणीवार आकडे तैयार किये गये और यह पाया गया कि (१) व्यापार, अन्य धधो, कला और दस्तकारियों तथा परमावश्यक सेवाओं में अनाज की खपत खेती-मजदूरी से कम पायी गयी, और (२) मजदूरी तथा अन्य धधो के मामले में आय का प्रभाव स्पष्ट है।

तालिका ५

विभिन्न आय-स्तर पर प्रति वयस्क अनाज की खपत

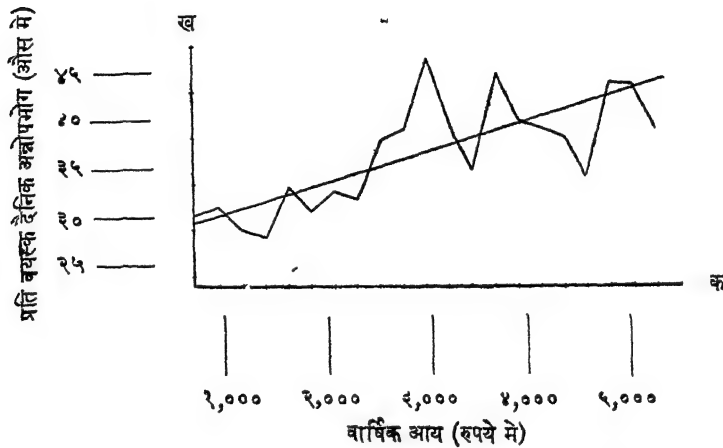
आय-स्तर (रुपये में)	प्रति परिवार औसत इकाई (औस में)	प्रति वयस्क आय (रुपये में)	प्रति वयस्क इकाई उपभोग (औस में)
२५० से कम	० ९९	१७० ०२	२६ ४६
२५० से ५००	२ ००	१९० ८५	२७ ६५
५०० से ७५०	३ २६	१८३ १६	२५ ०४
७५० से १,०००	४ १७	२०७ १२	२४ ३९
१,००० से १,५००	४ २६	२७६ १४	२८ ४०
१,५०० से २,०००	५ ०१	३४६ ६४	२८ ६७
२,००० से ३,०००	५ ३४	४५० ७४	३६ ७५
३,००० से ५,०००	६ ०२	६४६ ०८	३६ ५५
५,००० से अधिक	७ ४९	१,१०६ ८१	३५ ६९
औसत	३ ६१	३५२ ६९	२८ ९३

सबसे कम विचरण कला और दस्तकारी में है। आय स्तर और अनाज की खपत
श्रमिकों और बड़े भूस्वामियों के साथ भी यही बात है। तालिका ५ विभिन्न आय-स्तरों के लिए प्रति वयस्क
सबसे अधिक विचरण परमावश्यक सेवाओं में पाया प्रति दिन अनाज की खपत दर्शाती है।

आय-स्तर २५० रुपये और १,००० रुपये के बीच अन्न की खपत में अधिक विचरण नहीं है। इसका कारण प्रति वयस्क आय में मिल सकता है। प्रति वयस्क आय में बहुत ही थोड़ा विचरण है। फिर, अनाज खपत के स्तर का सामान्यतः आय से कोई मेल नहीं होता। एक हजार रुपये से दो हजार रुपये के बीच की आयवाला वर्ग पिछले वर्ग से कुछ भिन्न है। हाँ, जिन परिवारों की

रेखा का समीकरण इस प्रकार है $x = 25.26 + 0.04k$, जबकि 'ख' प्रति दिन प्रति वयस्क कुल अनाज खपत दर्शाता है और 'क' वार्षिक आय। 'ची वर्ग' (ची स्वयंवर) से परीक्षण करने के बाद उपर्युक्त रेखा बिल्कुल ठीक बैठती पायी गयी। रेखा के समीकरण से यह पाया जाता है कि आय में २५० रुपये की वृद्धि होने से अनाज खपत में ०.०४ औंस की वृद्धि होती है।

आय स्तर में अन्नोपभोग



आय २,००० रुपये से अधिक है, वे निश्चय ही अन्य वर्गों से भिन्न हैं। इस वर्ग की एक विशेषता यह है कि इसके परिवारों में से ६५ बड़े और मध्यम भूस्वामी परिवार हैं। इस वर्ग के ३७ परिवारों के पास खलिहान की देख-भाल करने के लिए स्थायी सेवक हैं।

विभिन्न आय स्तरों में अन्नोपभोग अर्थात् अनाज की खपत-सम्बन्धी ग्राफ तैयार किया गया। इस कार्य के लिए परिवारों को २१ आय-वर्गों में बाटा गया—२५० रुपये से कम से लेकर ५,००० रुपये से अधिक तक और एक से दूसरे वर्ग के बीच २५० रुपये के अन्तर के साथ। ग्राफ ने आय और अनाज खपत के बीच रेखीय झुकाव का संकेत दिया। अतः एक सीधी रेखा बैठ गयी।

भिन्न जाति, आय और धंधा वर्गों के लिए विचरण की तुलना करने हेतु विचरण गुणांक निकाला गया है।

वर्ग	प्रति वयस्क प्रति दिन खपत का विचरण गुणांक (प्रातिशत्य)
जाति	१४
आय	१६
धंधा	२३

इससे यह प्रकट है कि धंधा और आय जाति से अधिक विचरण दर्शाते हैं। धंधा और आय के प्रभाव को

अलग करने के लिए विचरण का विश्लेषण किया गया है और परिणाम नीचे दिये गये हैं। एक प्रति शत स्तर पर भी आय तथा धंधे के मामले में विचरण अनुपात बड़े ही महत्वपूर्ण पाये गये। अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धंधा और आय दोनों ही अनाज की कुल खपत पर प्रभाव डालते हैं।

उत्तम प्रकार के अनाज का उपभोग

इम गाँव में चावल एक मात्र उत्तम अनाज है और मुख्य घटिया अनाज है कुम्बु। कुल खपत में उत्तम अनाज के अनुपातीय उपभोग सम्बन्धी जातिवार आकड़े तालिका ६ में दिये गये हैं। जहाँ यादव लोग सबसे कम उत्तम अनाज खाते हैं, वहीं 'अन्य' श्रेणी में आनेवाले लोगो में इसकी खपत सबसे अधिक है। यद्यपि यादवों में उत्तम अनाज की खपत कम है, उनका कुल अन्नोपभोग (२९ १५ औंस) गाँव के औसत (२८ ९३ औंस) से अधिक है। अधिकांश यादव खेतिहर मजदूर और गडेरिये हैं तथा वे इनमें गरीब हैं कि चावल नहीं खरीद सकते। अतः वे घटिया अनाज अधिक खाते हैं और इसी कारण उत्तम अनाज की खपत कम है।

तालिका ६

विभिन्न जातियों में उत्तम अनुपातीय अन्नोपभोग

जाति वर्ग	कुल अन्नोपभोग में उत्तम अन्नोपभोग का प्रातिशत्य
नैकर	२५ ६२
नाडार	३८ ४९
यादव	८ ९९
श्रमिक	२६ ४९
सेबाएँ	३० ५०
'अन्य'	६३ ४०
शेष सभी	२७ ४०

'अन्य' वर्ग में उत्तम अन्नोपभोग का प्रातिशत्य इसलिए अधिक है कि इस वर्ग में ब्राह्मण, पिल्लै और मुदालियर लोग हैं और वे मुख्यतः चावल खाते हैं। इस वर्ग में के १५ परिवारों में से सात तो निरर्थक चावल ही खाते हैं। 'अन्य' के बाद नाडार वर्ग में उत्तम अन्नोपभोग का अधिक प्रातिशत्य है। यह इस कारण हो सकता है कि इसमें २० व्यापारी परिवार हैं और १४ परिवार ऐसे हैं जो किरानागिरी में लगे हैं। यदि इन जाति वर्गों को छोड़ दिया जाय तो बाकी सभी वर्गों में उत्तम अन्नोपभोग का स्तर कमोवेश एक ही है। प्रत्येक जाति में उत्तम अन्नोपभोग पर आय-स्तर के प्रभाव का परीक्षण करने हेतु प्रत्येक जाति के लिए विचरण गुणांक निकाला गया। यह देखा जाता है कि सभी जाति वर्गों में आय-स्तर का अन्नोपभोग निश्चित करने में प्रभाव पड़ता है। नैकर

तालिका ७

विभिन्न जातियों में आय-स्तर के अनुसार आनुपातिक उत्तम अन्नोपभोग का विचरण गुणांक

जाति वर्ग	विचरण गुणांक (प्रातिशत्य)
नैकर	२९ ६३
नाडार	४३ ९२
यादव	४९ ८८
मजदूर	३६ ०३
सेबाएँ	४८ ३३
अन्य	४७ ५६

और मजदूर जातियों में अन्य चार जातियों के बनिस्बत विचरण गुणांक कम है। नैकर में यह इस कारण हो सकता है कि १३५ परिवारों में से १०६ का मुख्य पेशा खेती है और उनका जो भी आय-स्तर हो वे अपने खेत में पैदा किये गये कुम्बु के उपभोग को प्राथमिकता देते हैं। मजदूरों को जिस-घटिया अनाज-के रूप में पारिश्रमिक

मिलता है और इसलिए आय-स्तर का उनके उपभोग स्वरूप पर कोई खास असर नहीं पड़ता।

धंधा और उत्तम अनाज

विभिन्न धंधों में लगे वर्गों में उत्तम अन्नोपभोग का अध्ययन तालिका ८ में किया गया है। तालिका ८ में प्रथम छ व्यावसायिक वर्ग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से सम्बन्धित है। इन छ में 'कला-कारीगरी' को छोड़ कर, उत्तम अन्नोपभोग के प्रातिशत्य में कोई विशेष विचरण नहीं है। 'कला-कारीगरी' में उत्तम अन्नोपभोग के आधिक्य का कारण यह है कि इस वर्ग के ३३ परिवारों में से १२ परिवार बढईगीरी, लोहारी और मोचीगीरी में लगे हैं तथा उन्हें परिश्रमिक कुम्बु के रूप में मिलता है। बाकी के २१ परिवार सुनारी सूघनी तैयार करने का काम, झाड़ू बनाने आदि में लगे हैं और उन्हें जिस के रूप में परिश्रमिक नहीं मिलता। ये लोग चावल अधिक खाते हैं, यह दिखाने के लिए 'कला-कारीगरी' वर्ग के परिवारों को दो श्रेणी में बाटा गया है—जो जिस के रूप में पारिश्रमिक पाते हैं तथा जो जिस के रूप में पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करते।

तालिका ८

विभिन्न धंधा-वर्गों में आनुपातिक उत्तम अन्नोपभोग

धंधा	उत्तम अनाज का आनुपातिक उपभोग (प्रातिशत्य)
बड़े भूस्वामी	२८ ३३
मध्यम	१९ ५९
छोटे	२५ २८
मजदूर	२० ०५
कला-कारीगरी	४१ ४७
परमावश्यक सेवाएँ	२१ ५७
व्यापारी-	५३ ४०
पेशेवर	५९ ८१

इन दोनों दलों में उत्तम अन्नोपभोग के प्रातिशत्य की तुलना इस प्रकार है जिन परिवारों को जिस के रूप में पारिश्रमिक मिलता है—३५ १६, जिन परिवारों को जिस के रूप में पारिश्रमिक नहीं मिलता—४४ ८४। यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि जिन परिवारों को जिस के रूप में पारिश्रमिक नहीं मिलता उनके यहाँ उत्तम अनाज का उपभोग अधिक है और चूंकि उनकी सभ्यता भी ज्यादा है, अतः 'कला-कारीगरी' वर्ग में सम्पूर्ण वर्ग के लिए उत्तम अन्नोपभोग का प्रातिशत्य अधिक है।

यदि हम 'कला-कारीगरी' वर्ग को बाद दे दे तो तालिका के प्रथम छ में से अन्य पाँच धंधा-वर्गों में उत्तम अन्नो-

तालिका ९

विभिन्न धंधों में आय-स्तर पर उत्तम अन्नोपभोग

धंधा-वर्ग	विचरण गुणांक (प्रातिशत्य)
बड़े भूस्वामी	२४ २२
मध्यम	३८ ५२
छोटे	५६ ३४
श्रमिक	५५ ९९
कला-कारीगरी	२९ ४१
परमावश्यक सेवाएँ	५८ ५०
व्यापार	५६ ७७
पेशे	२१ ५४

पभोग प्रातिशत्य १९ ५९ और २८ ३३ के बीच रहता है। व्यापारियों और पेशेवरों में उत्तम अन्नोपभोग का उच्च प्रातिशत्य इसलिए है कि एक-तिहाई व्यापारी और एक-चौथाई पेशेवर सिर्फ चावल ही खाते हैं।

प्रत्येक धधा वर्ग में उत्तम अन्नोपभोग पर आय के प्रभाव का अध्ययन विचरण गुणांक निकाल कर किया गया है।

सर्वाधिक विचरण परमावश्यक सेवाओं और व्यापार में लगे लोगों तथा छोटे भूस्वामियों में है। बड़े भूस्वामियों और पेशे में लगे लोगों में बहुत ही कम विचरण है, क्योंकि प्रथम में उनका आय-स्तर जो भी हो, घटिया अनाजों की खपत अधिक है और द्वितीय में उत्तम अन्नोपभोग अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तम अन्नोपभोग में आय का धधा वर्ग या जाति वर्ग से अधिक प्रभाव है।

आय से सम्बन्ध

तालिका १० विभिन्न आय-स्तर के लोगों में उत्तम अन्नोपभोग का अनुपात दर्शाती है।

तालिका १०

उत्तम अन्नोपभोग और विभिन्न आय-स्तर

आय स्तर (रुपये में)	उत्तम अनाज का उपभोग (प्रातिश-य)
२५० से कम	८ ५८
२५० से ५००	२० ००
५०० से ७५०	२४ ९२
७५० से १,०००	३४ ९७
१,००० से १,५००	२६ ३७
१,५०० से २,०००	२७ ३१
२,००० से ३,०००	२२ १८
३,००० से ५,०००	२९ ६६
५,००० से अधिक	४१ ०५

यदि ७५० रुपये से १,००० रुपये तथा २,००० रुपये से ३,००० रुपये के दो आय-स्तरो को बाद दे दे तो उत्तम अन्नोपभोग का प्रातिशत्य आय-स्तर में वृद्धि के साथ बढ़ता है। आय-स्तर ७५० रुपये से १,००० रुपये में उच्च प्रातिशत्य इसलिए पाया जाता है कि उस वर्ग के ५९ परिवारों में से २० धधा, 'कला-कारीगरी,' व्यापार और पेशेवर वर्ग के हैं, जो कि—जैसा कि पहले देखा जा चुका है— उत्तम अन्नोपभोग का उच्च प्रातिशत्य दर्शाते हैं। आय-वर्ग २,००० रुपये से ३,००० रुपये के अन्तर्गत २८ परिवारों में से छ यादवों के हैं जिन्होंने उत्तम अन्नोपभोग का न्यूनतम प्रातिशत्य दर्शाया है। इस आय-स्तर के प्रातिशत्य में गिरावट का यही कारण है।

सर्वोच्च आय वर्ग सर्वाधिक प्रातिशत्य दर्शाता है। इस वर्ग में अधिकतर बड़े खेतिहर और व्यापारी ही हैं।

जाति, आय और धधा वर्गों में उत्तम अन्नोपभोग के विचरण की तुलना करने हेतु विचरण गुणांक संगठित किये गये हैं। वे इस प्रकार हैं। जाति ५१ १८ प्रति शत, धधा ४४ ०५ प्रति शत, और आय ३३ १५ प्रति शत। आय के बनिस्बत जाति और धधा कारक अधिक विचरण लाते हैं।

इस गाँव में कुल अन्नोपभोग में आय और धधे का बड़ा प्रभाव है, जबकि उत्तम अन्नोपभोग जाति और धधा द्वारा प्रभावित है। यह भी पाया गया है कि धधा और जाति वर्ग के अन्तर्गत उत्तम अन्नोपभोग निर्धारित करने में आय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ●

हरसूद सामुदायिक विकास खण्ड का सर्वेक्षण और आयोजन

पूर्वी निमाड जिले में हरसूद सामुदायिक विकास खण्ड मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा इलाका है, जिसकी ९५ प्रति शत आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है। तथापि, इसमें कारीगर व आवश्यक कच्ची सामग्री उपलब्ध है और तैयार माल की बिक्री की सुविधाएँ मौजूद हैं, फलस्वरूप दुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास की सुन्दर सम्भाव्यताएँ उक्त क्षेत्र में हैं। नीलोखेड़ी रिथत छाठी ग्रामोद्योग विद्यालय में मध्य प्रदेश से प्रशिक्षण के लिए आये हुए बारह विरतार अधिकारियों (उद्योग) ने एक सर्वेक्षण किया था, जिससे उक्त तथ्य सामने आये हैं।

मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड (खण्डवा) जिले में सात सामुदायिक विकास खण्ड हैं। हरसूद सामुदायिक विकास खण्ड उनमें से एक है। उक्त विकास खण्ड का उद्घाटन २ अक्टूबर १९५३ के दिन हुआ था। पिल-हाल यह अपने विकास के द्वितीय चरण से हो कर गुजर रहा है। इसका क्षेत्रफल २२८३ वर्ग मील और आबादी ४४,५६८ है। इसमें १११ गाँव हैं। इन गाँवों को दस ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता वृत्तों में विभक्त किया गया है। इन वृत्तों के सदर मुकाम हरसूद, छनेरा, बह्मग्राम, पिपलानी, रेवापुर, बोरखेडा, माण्डला, बोरीसराय, भवानिया और बोधिया में हैं। खण्ड के सदर मुकाम से सर्वाधिक दूरी—१८ मील—पर अवस्थित वृत्त है माण्डला का। बरसात के मौसम में तीन ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता वृत्तों—माण्डला, बोरीसराय और भवानिया—का छोटे-छोटे नदी-नालों में बाढ़ आ जाने के कारण सदर मुकाम से व्यवहारत सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

भौगोलिक जानकारी

हरसूद विकास खण्ड का सदरमुकाम बड़ी लाइन (सेण्ट्रल रेल्वे) पर पड़ता है। रेल्वे स्टेशन तीन—हरसूद, सिवाजी और पिपलानी—हैं। खण्ड में १८ मील तक राज्य का राजमार्ग भी है। विकास खण्ड में अध-पक्की सड़कें भी हैं, जो हरसूद को खण्ड के खास-खास गाँवों

से मिलती हैं। इन सड़कों की कुल लम्बाई तकरीबन २० मील है। हरसूद विकास खण्ड में वार्षिक औसत वर्षा ३० इंच से ३५ इंच तक होती है। सर्दियों में न्यूनतम तापमान ४०° फर्नहाइट और गर्मियों में अधिकतम तापमान ११६° फर्नहाइट है। खण्ड में पाँच छोटी नदियाँ बहती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—तवा, गोडापचर, काली मचक, रूपारेल और फेकराल। कुल ९७,२२५ एकड़ भूमि पर खेती होती है और २,४९३ एकड़ अकृष्य बज्र है। पशु चराने के लिए २८,७१३ एकड़ भूमि स्थायी तौर पर चरागाह के रूप में रखी जाती है। हरसूद विकास खण्ड में एक महत्वपूर्ण मिवाजी जगली इलाका है। इसका क्षेत्रफल ४,६२२ एकड़ है। इसमें अच्छे गुण-स्तर का सागोन, नरम काठ तथा अन्य प्रकार का इमारती काठ मिलता है। अकृष्य बज्र भूमि के अलावा १२,०९५ एकड़ में पहाड़ आदि हैं। उक्त कृष्ट भूमि में से केवल २,८०१ एकड़ की ही सिचाई होती है। मुख्य सिचाई स्रोत कुएँ हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कच्चे बाध भी हैं, जिनसे सिचाई होती है।

पूर्वी निमाड जिले में हरसूद तहसील का सदर मुकाम है। हरसूद में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाएँ हैं। इस खण्ड के विभिन्न गाँवों में नौ उप-डाक घर (सब-पोस्ट आफिस) हैं। विकास खण्ड का १९५३ में उद्घाटन हुआ, उससे

पहले कुछ ही प्राथमिक विद्यालय थे। उनमें छात्र-संख्या २,५३७ थी। अब वहाँ पाँच माध्यमिक विद्यालय और दो हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, जिनमें क्रमशः ८१४ और ४१९ विद्यार्थी हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ शिक्षा केन्द्र, १५ वाचनालय और १४ मनोरंजन केन्द्र भी चल रहे हैं।

विभिन्न फसले

हरसूद विकास खण्ड की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक रूप से उपयुक्त है और इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि कपास हरसूद विकास खण्ड की एक महत्वपूर्ण नकद फसल है। मूंगफली तथा अन्य किस्म के तिलहन और कुछ अन्य नकद फसले भी क्षेत्र में बोयी जाती हैं। कुल २७,४२५ एकड़-भूमि पर कपास की खेती होती है और २३,३५७ एकड़ पर मूंगफली तथा अन्य तिलहनो की। खाद्यान्नों की फसलों में औसतन रूप से सबसे अधिक क्षेत्र (१४,४१४ एकड़) पर ज्वार की खेती होती है। इसके बाद धान का स्थान आता है और फिर गेहूँ का। इन दोनों की कृषि के अन्तर्गत क्रमशः ७,१३५ और ६,३८३ एकड़ भूमि हैं। चने की खेती ३,००८ एकड़ पर और मूंग, मोठ, मसूर आदि की १,३७५ एकड़ पर होती है। फलों में सर्वोच्च स्थान आम का है। उसका वार्षिक उत्पादन ४,२०० क्विण्टल है। अमरूद, नारंगी, नीबू तथा जामुन अन्य फल हैं, जो हरसूद में पैदा होते हैं। तरकारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलू है, जिसका कुल उत्पादन ४,२०० क्विण्टल है। आलू की खेती बीस एकड़ जमीन पर होती है। उत्पादन के परिणाम की दृष्टि से मिर्च का दूसरा स्थान है, जिसकी खेती ५०० एकड़ पर होती है और उत्पादन ३,१५० क्विण्टल है। फल गोभी, टमाटर, घनिया आदि भी क्षेत्र में बोये जाते हैं।

पशु धन

हरसूद विकास खण्ड में १९६१ की पशु गणना के अनुसार ५४,६५६ मवेशी हैं, जिनमें २२,६६३ दुधारू

और शेष कर्षक पशु हैं। कर्षक पशुओं में २६,८९० बैल, ५,१७२ बकरे, ३०४ घोड़े और २३,२०३ भैंसे तथा १४ भेड़ें हैं। दुधारू पशुओं में १५,०४५ गायें हैं और ७,०१८ भैंसे। औसतन एक गाय रोजाना एक पौण्ड और एक भैंस तीन से चार पौण्ड तक दूध देती है। दुधारू पशुओं की हालत बहुत खराब है और उनकी चराई अच्छी नहीं होती। सामान्यतः उन्हें अपने आप जंगल में चरने छोड़ दिया जाता है। करीब ९५ प्रति शत आबादी खेती में लगी है। शेष पाँच प्रति शत ही द्वितीय श्रेणी के काम-धंधों में लगी है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ समझा जाता है। ऐसा समझना है भी ठीक। विकास खण्ड में कुल ८३० कारीगर परिवार हैं। उनकी सघटना इस प्रकार है चर्मकार २१६, दर्जी ११६, बढई ११६, वेत और बास कारीगर ७५, कुम्भकार और ईंट पथार ७५, लुहार ५६, सुनार ५५, कपाम से बिनौला अलग करनेवाले और आटा पीसनेवाले ५५, तेलकार ३७, बुनकर ३०, पत्थर शिल्पकार ६, बन्दूक मरम्मत करनेवाले ४, तथा रोशा तेल निस्सारक २। खण्ड में कपास से बिनौले अलग करने के दो कारखाने हैं। इसके सिवाय एक तेल मिल और ११३ शक्ति चालित आटा चक्कियाँ हैं। ये सब उन विभिन्न स्थानों पर हैं, जहाँ बिजली उपलब्ध है। इन मिलों और कारखानों से कुल ८४ व्यक्तियों को मौसमी रोजगारी मिलती है। मध्यम स्तरीय उद्योगों की गुंजाइश केवल तभी बढ़ सकती है, जबकि शक्ति की पर्याप्त निमित्त पूर्ति हो। हरसूद में केवल एक शक्ति प्रजनक है, जो खण्ड के चार गाँवों को शक्ति और बिजली की पूर्ति करता है।

ग्रामोद्योगों की गुंजाइश

बस्तुतः विकास खण्ड में कुटीर और ग्राम उद्योगों की बहुत बड़ी गुंजाइश है। प्रायः सभी परम्परागत उद्योग खण्ड में चलते हैं, लेकिन यह एक खेद की बात है कि उन सभी की अवस्था बड़ी शिथिल है। स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धि और बिक्री-व्यवस्था सम्बन्धी सुवि-

घाएँ प्राप्त होने के बावजूद बेचारे असहायतावस्था में पड़े कारीगरों का उद्धार करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। देशी जूतियों, चप्पलों और कृषकों द्वारा उपयोजित अन्य चर्मोद्योगी उत्पादन की मांग है। खण्ड में पशु बहुत बड़ी संख्या में हैं और चर्म शोधक तथा चर्मकार आसानी से मृत पशु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन कारीगरों को बेहतरीन साधन-सरजाम प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए सहकारी जामा पहनाने की दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ, इन्हें सहकारी समितियों में शामिल करने के लिए मामूली स्तर पर प्रयास किये गये हैं। हरसूद विकास खण्ड में दो चर्मकार सहकारी समितियाँ हैं। कुछ और चर्मकार तथा चर्मशोधक सहकारी समितियों की गुंजाइश है।

मुख्यतः कृषि में

यद्यपि विकास खण्ड में ३० बुनकर परिवार है, लेकिन वे मुख्यतः कृषि में लगे हैं, यही बात तेलकारों तथा अन्य कारीगरों के सम्बन्ध में भी लागू होती है। कुटीर तथा ग्राम उद्योगों सम्बन्धी जो भी काम अब तक विस्तार अधिकारियों (उद्योग) ने हाथ में लिया है, वह हरसूद खास में ही। हरसूद में १९५८-५९ में एक बड़ईगिरी प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया और उसमें २९ प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसी वर्ष एक सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र का भी आयोजन हुआ, जहाँ चार वर्गों में ४६ व्यक्तियों ने उक्त कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि उक्त प्रशिक्षार्थियों के बाद तत्सम्बन्धी अनुवर्ती काम नहीं हुआ। विश्वास किया जाता है कि उक्त व्यक्तियों ने, खण्ड की प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें जिस काम का प्रशिक्षण दिया गया, उसके अलावा अन्य प्रकार के काम-धंधे अपनाये हैं।

विकास खण्ड में कुल ३८ सहकारी समितियाँ हैं, जिनकी सदस्य-संख्या १३,९८३ है। विस्तृत विवरण इस प्रकार है

समिति का नाम	संख्या	सदस्य
सेवा सहकारी समिति	३२	१२,८९५
विनय-व्यवस्था सहकारी समिति	१	४८५
बहुदेशीय सहकारी समिति	१	४६३
उन्नत कृषि सहकारी समिति	१	८३
चर्म सहकारी समिति	२	४२
कुम्भकारों व ईंट पथारों की सहकारी समिति	१	१५
योग	३८	१३,९८३

विकास खण्ड में १४ युवक दल, ३ महिला मण्डल और २ ग्राम सेवक इकाइयाँ हैं। औद्योगिक सहकारी समितियों में केवल चर्मकार सहकारी समिति ने ही सरकार के उद्योग विभाग से 'उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम' के अन्तर्गत ५,००० रुपये ऋण स्वरूप प्राप्त किये। बड़ईगिरी और लोहारगिरी के काम में लगे कारीगरों में १,७५० रुपये अनुदान स्वरूप वितरित हुए।

हरसूद विकास खण्ड में १९६०-६१ के दौरान जो चीजे बाहर से मगवायी गयी तथा जो बाहर भेजी गयी, उनका विवरण इस प्रकार है

मद	आयात		निर्यात	
	परिमाण (किण्टल में)	मूल्य (रुपये में)	परिमाण (किण्टल में)	मूल्य (रुपये में)
रूई	—	—	२,३४३ ५	५,००,०००
तिलहन	—	—	—	२२,०००
गेहूँ	—	—	२,२५० ०	१,०८,०००
चना	—	—	४१२ ५	१४३००
रोशा तेल	—	—	५ ५	—
साबुन	११२	१२,०००	—	—
मिल-	—	—	—	—
वस्त्र	—	७८,०००	—	—
चीनी	४५०	६०,०००	—	—
गुड	१६८	९,०००	—	—
जूता व चप्पल	—	१५,०००	—	—

हरसूद, छनेग, योगम्बेठा और बोरीमराय में एक-एक माप्ताहिक मण्डी हैं। ये चारों ही प्रधान मण्डियाँ हैं। ये मण्डियाँ मप्ताह के अलग-अलग दिनों में लगती हैं। इनके अलावा हरसूद, छनेरा और सिघाजी में एक-एक वार्षिक मेला लगता है। एक लाख से भी ज्यादा लोग इन मेलों में इकट्ठे होते हैं।

उपलब्ध कच्ची सामग्री और जन-शक्ति के आधार पर यह महसूस किया जाता है कि खादी, हाथ धान कुटाई और दाल तथा अन्न प्रशोधन, घानी तेल, अखाद्य तेल और साबुन, चर्म शोधन, कुम्भकारी, रेशा आदि जैसे कुटीर उद्योग विकास खण्ड में बिना किसी खाम कठिनाई के शुरू किये जा सकते हैं।

खादी उद्योग

वस्त्र मानव की तीन बुनियादी आवश्यकताओं में एक है। हरसूद विकास खण्ड में रूई का कुल उत्पादन ६,१२१ ५ क्विण्टल है। किसी सूती मिल के अभाव में ममूची रूई बाहर भेजी जाती है। यदि विकास खण्ड के लोग सूतकारों और बुनकरों की सहायता में खण्ड के अन्दर ही वस्त्र तैयार करने का ठोस इरादा करे, तो बहुत बड़ी तादाद में कारीगरों को काम मिल सकता है।

इस उद्योग में न केवल लोगों को बहुत बड़ी स्रया में रोजगारी प्रदान करने की ही क्षमता है, बल्कि इससे अच्छे गुण-स्तर के ज्यादा पौष्टिक चावल की अधिक प्रातिशत्य में सम्प्राप्ति भी होती है। हरसूद विकास खण्ड में प्रति वर्ष ३७,९७८ क्विण्टल धान पैदा होता है। खण्ड में ५,४८१ क्विण्टल चना और मूंग, उड़द आदि भी प्रति वर्ष पैदा होते हैं। फिलहाल हरसूद विकास खण्ड में १३ शक्ति-चालित आटा चक्कियाँ हैं। हलरों की सख्या आठ ही है। इन हलरों की मौसम कालीन क्षमता करीब १२,००० क्विण्टल है। शेष २५,९७८ क्विण्टल की कुटाई उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए हाथ से की जा सकती है। यह काम ५८ इकाइयाँ कर सकती हैं। एक टुकाई में दो ठेकियाँ और एक चक्की होती है, जिनसे छ व्यक्तियों को काम मिलता

है। उस प्रकार वर्ष में १५० दिन कुल ३४८ आदिमियों को काम मिल सकता है। अन्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग परंपरा में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए यह सुझाया जाता है कि कारीगरों की सख्या और धान की उपलब्धि के अनकूल सहकारी समितियाँ गठित की जा सकती हैं।

इसी प्रकार अनाज और दाल प्रशोधन कार्य भी चलाया जा सकता है, जिसमें अन्य ५८ व्यक्तियों को काम मिलेगा। विकास खण्ड के कर्मचारियों और उप-निर्देशक (उद्योग) के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान सुझाया गया कि यदि इस उद्योग के लिए नयी सहकारी समिति गठित करना सम्भव न हो, तो सम्बद्ध कारीगरों को अपने सदस्य बना कर पहले से चल रही सेवा सहकारी समितियाँ तथा बहुदेशीय सहकारी समितियाँ इस उद्योग का काम अपने हाथ में ले सकती हैं। इस प्रकार की समितियाँ भी राज्य की खादी और ग्रामोद्योग परंपरा से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यदि कोई सहकारी समिति अथवा पचायत किसी व्यक्ति का नाम प्रवर्तित करे, तो इस तरह के स्वतंत्र व्यक्तियों को भी रियायती दर पर उन्नत उपकरण दिये जा सकते हैं।

ग्रामीण तेल उद्योग

विकास खण्ड में सभी प्रकार के तिलहनो का कुल वार्षिक उत्पादन ३७,०१२ क्विण्टल के लगभग है। पर्याप्त दूध और दुग्धोत्पादन की कमी के कारण लोगों के लिए चिकनाई का मुख्य स्रोत तेल ही है। फिलहाल खण्ड में केवल एक ही एक्सपेलर है, जिसकी पेराई क्षमता मौसम काल में १४० क्विण्टल है।

प्रति व्यक्ति दो औसत दैनिक चिकनाई उपभोग के मानक स्तर के आधार पर हरसूद विकास खण्ड के ४४,५६८ व्यक्तियों की तेल सम्बन्धी वार्षिक आवश्यकता ८,४५५ क्विण्टल है। तिलहनो की इस मात्रा की पेराई में ग्रामीण तेल उद्योग ३०० में भी ज्यादा व्यक्तियों को पूर्णकालीन काम दे सकता है। तिलहनो की पेराई यदि धानियों में की जाय तो वैसा करने से मवेशियों के

लिए पौष्टिक खली की प्राप्ति भी होगी। अतिरिक्त तिलहन बाहर भेजे जा सकते हैं।

तेलकारो के ३० परिवार विकास खण्ड में हैं। उन्होंने अपना परम्परागत पेशा छोड़ दिया है और खेती करने लगे हैं। उपयुक्त उत्प्रेरणा व प्रोत्साहन देने पर ये परिवार फिर से अपना मूल धंधा अपना सकते हैं। साथ ही गाँव में उपलब्ध पशु-शक्ति का भी ग्रामीण तेल उद्योग में लाभदायक उपयोग किया जा सकता है।

ग्रामीण चर्मोद्योग

पशुओं के शवों से विभिन्न उत्पादनों की व्यवस्थित सम्प्राप्ति और उपयोग का बहुत बड़ा महत्व है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के प्रत्याशित स्रोत, इस उद्योग, के सुनियोजित और वैज्ञानिक विस्तार का बहुत बड़ा महत्व है।

हरमूद विकास खण्ड में मवेशियों की कुल संख्या ७७,७०० है। उपलब्ध आकड़ों के अनुसार केवल १,७०० मृत पशुओं का ही उपयोग होता है तथा उनका भी केवल चर्मशोधन की दृष्टि से ही। पशुओं के सहज मात प्रति शत मृत्योनुपात के अनुसार विकास खण्ड में ५,४३९ पशु प्रति वर्ष मरने चाहिये। फिलहाल शव छेदन पुराने तौर-तरीकों और औजारों से किया जाता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि शोधित चर्म निम्न स्तरीय होता है।

स्वाभाविक मौत से मरे मवेशियों के शवों का उपयोग करने के लिए विकास खण्ड में कम से कम तीन आदर्श चर्म शोधन केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं। तथापि, इन केन्द्रों के लिए स्थल का चयन करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। चर्म शोधन केन्द्र उन स्थानों पर खोले जाने चाहिये, जहाँ पशुओं की अच्छी-खासी संख्या और चर्मशोधकों का जमाव हो। इसलिए यह आवश्यक है कि ये केन्द्र ऐसे स्थानों पर हों, जहाँ बैलगाड़ी तथा गाँवों में उपलब्ध आवागमन के अन्य ऐसे ही साधनों से पहुँचा जा सके। इन केन्द्रों के इर्द-गिर्द पाँच-सात मील के घेरे में कम से कम पाँच शवछेदन केन्द्र होने चाहिये।

इन शवछेदन केन्द्रों से चर्म शोधन केन्द्रों को बराबर खाले मिलती रहनी चाहिये। इन सब केन्द्रों पर वर्ष भर ३०-४० आदमियों को पूरे समय की रोजगारी मिल सकती है।

आदर्श चर्म शोधन केन्द्र में खालों के शोधन के अलावा हड्डी चूर्ण, मांस खाद, सरेण आदि जैसे उप उत्पादनों के उत्पादन का काम भी हाथ में लिया जा सकता है। इससे चर्म शोधकों को अतिरिक्त रोजगारी और अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी।

अखाद्य तेल और साबुन

कपडा धोने के साबुन की सभी जगह मांग है और हरमूद विकास खण्ड कोई अपवाद नहीं है। चूँकि क्षेत्र में कोई साबुन उत्पादन कारखाना नहीं है, इसलिए आवश्यक मात्रा में साबुन बाहर से मँगवाया जाता है। वर्ष में कुल १२,००० रुपये मूल्य का ११० क्विण्टल साबुन बाहर से आयात किया जाता है। 'सी' श्रेणी का साबुन उत्पादन केन्द्र खोलने की गुंजाइश है। इस क्षेत्र में महुआ बीज अच्छी-खासी मात्रा में मिलते हैं। विकास खण्ड में नीम के पेड़ों की भी अच्छी संख्या है। अच्छे गुण-स्तर के साबुन का उत्पादन करने के लिए अखाद्य तिलहनो के इन स्रोतों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। कास्टिक सोडा, नारियल अथवा खाखन तेल, मोडियम सिलीकेट आदि जैसी अन्य आवश्यक कच्ची सामग्री बाहर से लायी जा सकती है।

कुम्भकार परिवारों की संख्या ४० है। वे मुख्यतः खपरैल बनाते हैं, लेकिन घरेलू उपयोग के बर्तन भी वे तैयार करते हैं। वे पुराने जीर्ण-शीर्ण चाक तथा अन्य उपकरणों का व्यवहार करते हैं। इस उद्योग को सुव्यवस्थित गानगण पुनर्जीवन कार्यक्रमों के लिए यह परमावश्यक है कि कुम्भकारों में बेहतरीन तकनीकों और उपकरणों के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाया जाय।

भावी विकास कार्यक्रम

विकास खण्ड का चतुर्दिक विकास करने के लिए खण्ड अधिकारियों ने वित्तीय तथा भौतिक साधन-स्रोतों

की उपलब्धि के आधार पर आगामी पाँच वर्ष अथवा ऐसी ही कुछ अवधि के लिए एक योजना बनायी और लक्ष्यांक निर्धारित किये हैं। कृषि, पशु-पालन, मत्स्य-पालन, सिंचाई, सहकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, उद्योग आदि की योजनाएँ बनायी जा चुकी हैं। इनमें से प्रत्येक की योजना का सारांश नीचे दिया जाता है

कृषि बेहतरनी तथा उन्नत कृषि-पद्धतियाँ प्रारम्भ करने के लिए साधन-संरक्षकों के प्रात्यक्षिक सगठित किये जायेंगे। ये उपकरण उनका विस्तृत प्रचार और उनकी उपयोगिता का प्रदर्शन करने के लिए गाँवों में रखे जायेंगे। प्रति वर्ष ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता वृत्तों में दो आदर्श 'फार्म' स्थापित करने की योजना है। खरीफ और रबी की फसल में उत्पादन-प्रतियोगिता में पाँच-पाँच हजार रुपये के दो पुरस्कार दिये जायेंगे। पौधा संरक्षण कार्यक्रम के लिए पौधा संरक्षण उपकरण, कीट-नाशक दवा आदि खरीद कर ग्राम सहायक के पास रखी जायेंगी।

पशु-पालन भवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए विभिन्न गाँवों में अच्छी नस्ल के २४ साण्ड रखे जाने का प्रस्ताव है। बीमार पशुओं को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता के पास एक-एक औषध-पेटी रखी जायेंगी। पाँचसाला अवधि में २० हस्तिालयों का निर्माण किया जायेगा। विकास खण्ड में प्रति वर्ष दस मुर्गी-पालन इकाइयाँ शुरू की जायेंगी।

सिंचाई छोटे-छोटे बाध बाध कर और कुए खोद कर विकास खण्ड में सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जायेगा। आगामी पाँच वर्ष में ३० सिंचाई कुए खोदने की योजना है, जिनसे ९० एकड़ जमीन को सिंचाई हो सकेगी। प्रति वर्ष एक-एक यानी पाँच वर्ष में पाँच छोटे-छोटे बाध बाधने का प्रस्ताव है। सिंचाई के लिए कुए 'गालने' के लिए ३२ किसानों को उपदान दिया जायेगा। आगामी पाँच वर्ष की अवधि में करीब छ सौ एकड़ कृष्य बजर भूमि की पुनर्वाप्ति होगी।

शक्ति हरसूद बिजली घर को चम्बल बिजली घर से सम्बद्ध कर दिया जायेगा।

सहकार सभी कृषक और कारीगर परिवारों को सहकारी जामा पहना देने की योजना है। संयुक्त सहकारी कृषि का भी प्रारम्भ किया जायेगा।

उद्योग दीर्घ, लघु तथा ग्राम उद्योगों के लिए कोई व्यापक व विस्तृत कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। तथापि, दस औद्योगिक सहकारी समितियाँ बनायी जायेंगी। एक ग्रामीण कार्यगृह का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया जायेगा।

स्वास्थ्य पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना, गन्दे पानी के बहाव के लिए नालियाँ और स्नानघर, स्वच्छ शौचालय व धूम-विहीन चूल्हे बनाना तथा रास्तों में 'खुर्रें' बनाना कार्यक्रम का उद्देश्य है। पीने के पानी के लिए नये २५ कुए तैयार किये जायेंगे। ये कुए फिल-हाल जो कुए हैं उनके अतिरिक्त होंगे। स्नानघर, शौचालय और धूम-विहीन चूल्हों के सम्बन्ध में लक्ष्यांक क्रमश ७००, ३०० और ७०० हैं।

शिक्षा विद्यालय भवन और शिक्षक निवास बनाना, शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्रावास तथा बाल-बाडियों का निर्माण शिक्षा कार्यक्रम में शामिल है। समाज शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पचायत घर और सामुदायिक चबूतरों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा। प्रदर्शनियो, ग्राम नेता शिविरो, विकसित क्षेत्रों के भ्रमण का भी आयोजन किया जायेगा।

अलग-अलग पन्द्रह गाँवों में पन्द्रह पचायत घर बनाने की योजना है। इसी प्रकार ३० खुले सामुदायिक चबूतरे बनाये जायेंगे। सिंचाजी और छनेरा में प्रति वर्ष वार्षिक मेलों के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। आगामी पाँच वर्ष में छ ग्राम नेता शिविर आयोजित किये जायेंगे।

नीलोखड़ी (पंजाब) ३ दिसम्बर १९६३

तेल उत्पादक सहकारों को सुझाव

त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्ति

तिलहन खरीद, उनके भाण्डारीकरण में सावधानी बरतने, तेल व खली को निकासी, धानियों की क्षमता के परिपूर्ण उपयोग और उत्पादन खर्च, धानी से तेल सम्प्राप्ति, तिलहनो के दैनिक बाजार भाव आदि से सम्बन्धित रिकार्ड रखने के बारे में प्रस्तुत लेख में अनेक सुझाव दिये गये हैं। तेलकार सहकारी समितियों को अपना काम-धाम ठोस व्यावसायिक आधार पर संगठित करने की दिशा में इन सुझावों से पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिये।

कुछ तेल उत्पादक सहकारी समितियाँ अपने वाणिज्य में घाटा उठाती हैं। इस प्रकार के घाटे के कारणों का विश्लेषण और उन्हें दूर करने के साधनों पर विचार किया जा रहा है। करीब डेढ़-सौ तेल उत्पादक सहकारी समितियों का निकट से अध्ययन करने और अलग-अलग कारीगरों के साथ तथा समिति, जिला और राज्य स्तर पर उनकी बैठकों में इस समस्या पर चर्चा करने के बाद लेखक इस नतीजे पर पहुँचा है कि कुछ समितियों की कार्यशीलताएँ अलाभदायक होने के कारक ये हो सकते हैं (१) तेल तथा तिलहनो के भावों में उतार-चढ़ाव, (२) पेरार्ड से तेल की कम सम्प्राप्ति, (३) पारिमाणिक दृष्टि से न्यून उत्पादन, (४) ऊपरी खर्चों का आधिक्य, और (५) विवेकहीनता व अव्यवस्था।

खरीद

समितियों का कार्य संचालन ठोस आधार पर हो, इसके लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि उसमें जो खामिया हैं उनका सही-सही पता लगाया जाय और फिर उन्हें दूर करने के लिए प्रभावक कदम उठाये जायें। यह भी आवश्यक है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि ये दोष उन समितियों में न घुस पायें जो अन्यथा ठोस हैं तथा नवगठित हैं।

अन्य अनेक ग्रामोद्योगों के विपरीत ग्रामीण तेल उद्योग में काफी पूँजी परिव्यय की आवश्यकता पड़ती है। तैयार माल यानी तेल व खली के मूल्य में लगभग ८५

प्रति शत हिस्सा कच्ची सामग्री का होता है। तिलहन खरीद का भाव और उनके मूल्य तथा गुण का सम्बन्ध लाभ अथवा हानि की सीमा निर्धारित करता है। जब खरीद की जाय तो प्रत्येक बार समय, स्थान, गुण और भाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में इस बात को तर्जनी दी जाय कि अनुभवी व्यक्ति तत्सम्बन्धी पक्षों पर विचार करे। इस काम के लिए प्रत्येक समिति में एक छोटी-सी त्रि-सदस्यीय समिति नियुक्त की जा सकती है। कुछ लोग कम कीमत के लिए सौदा करते हैं लेकिन गुण पर विशेष ध्यान नहीं देते। अवश्य ही यह याद रखना चाहिए कि अगर तिलहन अच्छे खरीदे जाते हैं तो उनसे प्राप्त तेल अच्छे गुण-स्तर का और सुवासित होगा, जिसका उपभोक्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

कभी-कभी दूर-दूर से तिलहन खरीद कर लाये जाते हैं, जबकि स्थानीय रूप से वैसे तिलहन उपलब्ध है। इससे बचना चाहिये, क्योंकि वैसी अवस्था में परिवहन और आवागमन पर बहुत खर्च हो जाता है। खरीद का काम कुछ समितियाँ मिल कर कर सकती हैं। एक समिति अपने लिए खरीद करते वक्त अपनी पड़ोसिन समिति के लिए भी वैसा कर सकती है।

तिलहन भाण्डारीकरण

अपने वित्तीय साधन-स्रोतों के अनुसार समितियाँ फसल कटाई के वक्त तिलहन खरीद कर उनका भाण्डारीकरण कर सकती हैं। उपलब्ध सीमित

धनराशि का उपयोग करने में विवेक और दूरदर्शिता से काम लेना आवश्यक है। फमल कटार्ट गुरु होने से पहले समिति को चाहिये कि वह कोशिश करके तेल व खली के पूरे स्टॉक की निकासी कर दे। मौसम काल में तिलहन भाण्डारीकरण के लिए अधिकतम धनराशि जुटाने हेतु सदस्यो तथा गैर सदस्य उपभोक्ताओं में जो भी बकाया हो, वह वसूल कर लिया जाय। इस प्रकार के विवेक और दूरदर्शिता से निश्चय ही भारी लाभ होगा। लेकिन मूंगफली के मामले में बिक्री दर निर्धारित करने में केवल इस एक ही बात का हाथ नहीं रहता कि यह फमल कटार्ट का मौसम है अथवा नहीं। अगर औद्योगिक क्षेत्र में तेल का अन्तर्गहन कभी भी उच्च हो तो मूंगफली के भाव भी बढ़ जायेंगे, फिर चाहे फमल-कटार्ट का मौसम ही क्यों न हो। इसी प्रकार अगर मूंगफली की खली की विदेशी बाजारों में माग नहीं हो और तत्सम्बन्धी सौदे नहीं होते, तो तेल के भाव बढ़ जायेंगे, क्योंकि व्यापारी खली की बिक्री में जो नुकसान होता है, तेल की बिक्री में उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। इन कारकों के कारण ही कभी-कभी हम देखते हैं कि मूंगफली और तेल के भावों में कोई सम्बन्ध नहीं होता। मूंगफली के तेज होने पर भी तेल सस्ता और तेल के भावों में तेजी होने पर भी मूंगफली सस्ती होने के उदाहरण देखने में आते हैं। इसलिए मूंगफली की पेराई का काम करनेवाली समितियों को चाहिये कि वे बाजार की सही-सही विवेकपूर्ण जानकारी प्राप्त करे अन्यथा वे आसानी से गुमराह हो सकती हैं।

भाण्डारीकरण और गुण-स्तर

जहाँ कहीं गोदाम प्राप्ति की समस्या नहीं हो वहाँ छिलके सहित मूंगफली का भाण्डारीकरण करना चाहिये, क्योंकि मूंगफली के दाने की अपेक्षा पूरी-की-पूरी मूंगफली ज्यादा दिनों तक टिकती है। रथानाभाव के कारण यदि मूंगफली के दानों का भाण्डारीकरण किया जाता है तो यह ध्यान रखना चाहिये कि गोदाम हवादार और आर्द्रता रहित है। भाण्डारीकरण से पूर्व

दानों को अच्छी तरह गुखा लेना चाहिये, क्योंकि विररीता-वस्था में डकट्टे रहने और गर्मी के कारण उनमें फफून्दा पैदा हो जाती है। कीटों और चूहों में रक्षा करने हेतु गोदाम पर निरन्तर ध्यान देते रहना होगा। मूंगफली के दाने का चार-पाँच महीने से अधिक समय तक भाण्डारीकरण नहीं किया जा सकता। इस अवधि में भी उन्हें समय-समय पर बाहर फैला कर सुखाते रहना चाहिये।

इसी प्रकार बोरियो में डाल कर रखने पर तिल (जिजली) भी भाण्डारीकरण के मामले में बड़ा निम्न कोटीय है। जिजली को छ महीने से ज्यादा भाण्डारीकरण की स्थिति में नहीं रखना चाहिये। भाण्डारीकरण की दीर्घ अवधि के कारण उस स्थिति में जो हानि होती है, वह काफी अधिक होती है। बोरियो में भरने से पहले जिजली तिलहन को अच्छी तरह धो कर उसकी सभी मिट्टी और कीचड़ आदि दूर कर देने चाहिये। कीचड़ लगा रह जाने पर वह जल्दी विगड़ जाता है।

उत्पादन का परिमाण

तिलहनो के मामले में जहाँ उनके भाण्डारीकरण पर जोर दिया जाता है, तेल और खली के सम्बन्ध में जोर इस बात पर रहता है कि उनकी निकासी जल्दी से जल्दी हो। कुछ ऐसी समितियों के उदाहरण हैं कि उन्होंने तेल के भाव तेज होने की आशा में तेल जमा करके रखा और फिर उन्हें घाटा हुआ। हमारे पास जब पैसा सीमित हो तो तैयार माल के रूप में उसे दीर्घ काल तक बन्द करके रखना बुद्धिमानी नहीं है। विशेष कर खली तो तैयार होते ही बेच देनी चाहिये, क्योंकि उसे ज्यादा दिनों तक रखने से उसके वजन में, सूखने के कारण, कमी होती है और फलस्वरूप हानि उठानी होती है। यदि फफून्दा न लगने देने के लिए खास ध्यान नहीं दिया जाय तो उसमें समीर उठ आती है।

किसी समिति की सभी धानियों को उनकी पूरी क्षमता भर काम में लगाये रखना न केवल इसलिए आवश्यक है कि सदस्यों को पूरे समय का काम देना पड़ता है बल्कि इसलिए भी कि जो सकल लाभ हो

वह समिति के बन्धे खर्च पूरे करने के लिए पर्याप्त होना चाहिये। लेकिन अधिकांश समितियों के मामले में ऐसा देखने में आता है कि तेल की विक्रय व्यवस्था में कठिनाई, उपलब्ध पूँजी की अपर्याप्तता आदि जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण, उनकी पूरी क्षमता का उपयोग कभी भी नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप उत्पादन और बिक्री के जरिये प्राप्त सकल लाभ व्यवस्था-खर्च तथा अन्य छिट-पुट खर्च से कम होता है और फलस्वरूप समितियों को विशुद्ध घाटा उठाना पड़ता है। समितियों की प्रशासनात्मक आवश्यकताएँ, उनके उत्पादन का परिमाण और प्रति बोरी (८० किलोग्राम) अपेक्षित औसत सकल लाभ जैसे पहलुओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद यह हिमाब लगाया जाता है कि एक समिति व्यवस्था-खर्च तथा अन्य छिटपुट खर्चों पर

अपनी बिक्री के दो प्रति शत से अधिक व्यय नहीं कर सकती। व्यवस्था और छिटपुट खर्चों में ये बातें शामिल हैं वेतन खर्च, यात्रा व्यय, किराया, बिजली खर्च, साफ-सफाई आदि (पारिवारिक और बैलो की चराई का खर्च अलग)।

बाजार अध्ययन

मूंगफली के बीजों की एक बोरी (८० किलोग्राम) की पैराई करने पर एक समिति को औसत कितना सकल लाभ प्राप्त हो सकता है, इसका हिसाब लगाने के लिए मद्रास के बाजार में लगातार लगभग चार महीने तक बीजों, तेल और खली का बिक्री मूल्य क्या रहा, इस सम्बन्ध में अध्ययन किया गया। सग्रहीत आकड़े नीचे दिये जाते हैं

मूंगफली के ८० किलोग्राम दानों और ४२ प्रति शत के हिसाब से उनसे प्राप्त तेल तथा खली की दरे

तारीख	८० किलोग्राम मूंगफली के दानों का मूल्य (रु में)	३३ ६ किलोग्राम (४२ प्रति शत) तेल का मूल्य (रु में)	४६ ६ किलोग्राम (५८ प्रति शत) खली का मूल्य (रु में)	कालम ३ व ४ का योग (रु में)	कालम ५ व ६ में अन्तर (रु में)
१	२	३	४	५	६
४-१०-६२	७०	५६ ००	१९ ४२	७५ ४२	+५ ४२
२२-१०-६२	६९	५९ ४७	१९ ९०	७९ ३७	+१० ३७
३०-१०-६२	६९	५९ ४७	२० ०१	७९ ४८	+१० ४८
१२-११-६२	७०	६० १४	२० ०१	८० १५	+१० १५
२७-११-६२	६९	५६ ४४	२० ०१	७६ ४५	+७ ४५
७-१२-६२	६८	५३ ७६	१९ ४२	७३ १८	+५ १८
१८-१२-६२	६८	५४ ००	१९ ४२	७३ ४२	+५ ४२
३१-१२-६२	६८	५४ ७६	१९ ४२	७४ १८	+६ १८
९-१-६३	६८	५३ ७६	१८ ८५	७२ ६१	+४ ६१
२९-१-६३	६८	५४ ९३	१८ ८५	७३ ७८	+५ ७८
३१-१-६३	६८	५४ ४३	१८ ८५	७३ २८	+५ २८
८-२-६३	६८	५४ २६	१८ ८५	७३ ११	+५ ११
१५-२-६३	६७	५३ ५९	१८ ८५	७२ ४४	+५ ४४
१९-२-६३	६८	५४ ६०	१८ ६८	७३ २८	+५ २८

टिप्पणी मूंगफली के दानों की वह कीमत ली गयी है जो सर्दी की फसल के लिए उद्घुत की गयी। सम्बद्ध दिन में तेल व खली का जो कम से कम भाव रहा वह लिया गया है। + सकल लाभ।

उक्त आकड़ों से हम यह समझ सकते हैं कि पेरित मूंगफली की प्रति बोरी पीछे औसत सकल लाभ करीब ६ ५० रुपये (कालम ६ का औसत) है। इसमें से समिति पाँच रुपये पारिश्रमिक और बैलों के चारे पर खर्च करती है। शेष १ ५० रुपये में से समिति को व्यवस्था खर्च और छिटपुट खर्चों की पूर्ति करनी पड़ती है तथा विशुद्ध लाभ भी कमाना पड़ता है। ऐसा पाया गया है कि एक समिति को अगर वह सहकारी आधार पर काम करती है तो प्रति माह कम से कम ९० रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यह खर्च पूरा करने के बाद यदि समिति को लगभग ३० रुपये मासिक विशुद्ध लाभ (जोकि साधारण-सा ही है) भी कमाना है, तो उसका सकल लाभ १२० रुपये मासिक होना चाहिये, जिसके माने हैं कि प्रति माह कम से कम ८० बोरी मूंगफली के दानों की पेराई की जाय। चूँकि और भी कुछ अप्रत्याशित खर्च करने पड़ सकते हैं, इसलिए कम से कम १०० बोरियों की प्रति माह पेराई करना बेहतर है। मूंगफली की पेराई में लगी यदि कोई समिति इससे कम पेराई करती है तो घाटे का अन्देश है। जिजली व सरसो जैसे तिलहनो की पेराई का काम करनेवाली समितियाँ व्यवस्था खर्च तथा छिटपुट खर्च में कुल बिक्री के तीन प्रति शत तक खर्च कर सकती हैं, क्योंकि इनमें सकल लाभ का अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से अधिक होता है।

लेखा परीक्षण सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए समितियाँ हिसाब-किताब रखती हैं। इस हिसाब-किताब के अलावा कुछ अन्य ऐसे रेकार्ड हैं जो लेखा-परीक्षण के लिए रखने आवश्यक नहीं हैं, लेकिन समितियों के लिए बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। ये रेकार्ड हैं उत्पादन खर्च रजिस्टर, सम्प्राप्ति निर्धारण रजिस्टर, दैनिक बाजार भाव रजिस्टर, उत्पादन तथा बिक्री में कमी-वृद्धि दर्शानेवाले ग्राफ आदि। प्रत्येक बार खरीदे गये तिलहनो का, तेल और खली का बिक्री मूल्य निर्धारित करने से पहले, उत्पादन खर्च निकाल लेना चाहिये। यथा सम्भव प्रति माह स्टॉक का मिलान करना चाहिये और उस आधार पर समिति की माली हालत समझने के लिए तलपट बनायी जा सकती है।

यदि समिति के कार्य संचालन में ये सब सुझाव कार्यान्वित किये जायें तो सदस्यों को नियमित और पूर्ण रोजगारी देते हुए तथा उपभोक्ताओं को अच्छा तेल उपलब्ध करवाते हुए उसकी कार्यशीलताओं को ठोस आधार पर विकसित किया जा सकता है। ऐसा करते हुए एक समिति चार-पाँच वर्ष में अपने लाभ में से पर्याप्त वित्तीय आरक्षण जमा कर आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर सकती है।

मद्रास २९ अगस्त १९६३

हमारे मस्तिष्क में जब तक प्रखरता मौजूद रहती है, वह पार्थिव सीमाओं के बन्धन में नहीं रहता; काल और दिगन्त के उस पार अनन्त तक उसकी पहुँच होती है। मानव होने का अर्थ है अपने को ऊपर उठाने में समर्थ होना। पूर्ण आयु मिलने पर भी एक जीवन में इन्सान कितना क्या कर सकता है ! व्यक्ति विशेष के कार्य का अर्थ और मूल्य सिर्फ उस समाज और इतिहास के विस्तृत सदर्भ में ही हो सकता है, जिसमें वह अपनी लघु भूमिका अदा कर रहा हो।

—अर्नाल्ड जे टायनबी जेनस एट स्लेवण्टी फ्राइव ।



एक राजस्थानी गाँव में कुम्भकारी उद्योग

राजस्थान के प्रायः सभी गाँवों में मिट्टी के बरतन आदि बनाने का काम एक खास जाति, जिसे कुम्हार कहा जाता है, करती है। फालना गाँव (तहसील बाली, जिला पाली) में भी कुम्हार जाति ही मिट्टी के बरतन आदि बनाती है। गाँव में किये गये सर्वेक्षण (१९६१-६२) के अनुसार वहाँ आठ कुम्हार परिवार निवास करते हैं। उक्त आठ परिवारों में से एक परिवार गाँव में १९४२ में आकर बसा तथा जो आज गाँव में कुम्हारी का काम न करके बुनाई का काम करता है, क्योंकि गाँव में बुनाई करनेवाला कोई भी परिवार नहीं था तथा बाहर से आनेवाला कुम्हार परिवार बुनाई का काम ही जानता था। इस प्रकार कुम्हारी उद्योग में सात परिवार ही लगे हैं। इन सात परिवारों की कुल जनसंख्या ३५ है, जिसमें २१ पुरुष व १४ स्त्रियाँ हैं। सातों कुम्हार परिवार गाँववालों के लिए भोजन बनाने के बरतन, पानी के मटके, ईंटे, खपरैल तथा गेड़े (earthen bucket) आदि बनाते हैं। इन सब में गेड़ का प्रमुख स्थान है, क्योंकि गाँव में रूट्ट द्वारा सिचाई की जाती है, जिसमें मिट्टी की गेड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। सभी कुम्हार बरतन आदि बनाने के लिए स्थानीय तालाब की मिट्टी का ही उपयोग करने हैं। जहाँ तक काम में लाये जानेवाले औजारों का सवाल है, प्रायः सभी

कुम्हार आज भी परम्परागत औजारों व चाको का ही प्रयोग करते हैं।

मिट्टी से बननेवाली चीजों में राजस्थानी ग्राम समुदाय में चिलम का जो स्थान है वही स्थान यहाँ की चिलम का है। चिलम बनाने का काम गाँव के कुम्हारों को नहीं आता। गाँववाले चिलम पास के कस्बों या लगनेवाले मेलों से खरीद कर लाते हैं, जो साचे से बनी होती है। कहने का आशय यह है कि गाँव के कुम्हार साचे में बननेवाली वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते। यह भी देखने में आया है कि गाँव के सभी कुम्हार परिवार पुराने विचारों के हैं और परम्परा से चले आ रहे विश्वासों का यथा शक्ति पालन करते हैं। शिक्षा का प्रसार इस जाति में सतोषप्रद नहीं है। साधारण तौर पर इनकी आर्थिक अवस्था सोचनीय ही है।

आर्थिक अवस्था

गाँव का कुम्हारी उद्योग वर्ष में आठ माह कुम्हार परिवारों को काम प्रदान करता है। बरसात में कुम्हारी उद्योग नहीं चल पाता। अतः सात परिवारों में कुम्हारी के साथ-साथ खेती का (ज्यादातर खरीफ की फसल का) काम भी किया जाता है। सात परिवारों में से तीन परिवार अपनी वार्षिक आय का बड़ा भाग खेती से प्राप्त

करते हैं, जबकि केवल चार कुम्हार परिवार ही कुम्भकारी उद्योग से अपनी वार्षिक आय का बड़ा भाग प्राप्त करते हैं। निम्न तालिका में हर परिवार की वार्षिक आय का विवरण दिया गया है।

क्रम सख्या	कृषि व पशु- पालन	श्रमि- काई	कुम्भ- कारी	अन्य	कुल वार्षिक आय
१	२०६	—	८११	९००	१,९१७
२	१७४	—	६३०	—	८०४
३	५७०	—	४३७	—	१,०१७
४	२१५	—	९१८	—	१,१३३
५	४६९	३००	१९९	—	९६८
६	१,८९४	—	४८३	—	२,३७७
७	७२१	४२०	४२०	—	१,५६१
योग	४,२४९	७२०	३,८९८	९००	९,७६७

उपर्युक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि कृषि से आय कुम्हारी उद्योग के मुकाबले में ३५१ रुपये अधिक है तथा इन सातों परिवारों की वार्षिक आय में काफी असमानता है। सहायक धंधे के रूप में कृषि, जो एक अनियमित आय प्रदान करनेवाला धंधा है, इन सातों परिवारों को आय प्रदान करती है। इनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय २७९ रुपये आती है, जो राजस्थान के प्रति व्यक्ति अनुमानित औसत आय ३३२ रुपये (मन् १९६०-६१ में) से कम है। इतनी कम औसत वार्षिक आय पर गुजारा करना बड़ा कठिन रहता है। फलस्वरूप वे ऊँची ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं और

किसी तरह अपना निर्वाह करते हैं। सात परिवारों में से चार परिवारों को अपना रोजमर्रा का खर्च चलाने हेतु २४ प्रति शत ब्याज दर पर ३,६०० रुपये ऋण-स्वरूप लेने पड़े। इतनी ऊँची ब्याज दर पर ये कुम्हारी उद्योग में लगे रह कर कठिनाई से ही गुजर-बसर कर पाते हैं।

चन्द सुझाव

१ कुम्हारी उद्योग का स्तर ऊँचा उठाने हेतु राज्य सरकार व ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही अन्य सामाजिक संस्थाओं को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये। विकास योजनाओं में इस कुटीर उद्योग को विकसित करने हेतु ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।

२ कुम्हारी उद्योग को आज की बदलती हुई परिस्थितियों में दृढ़ आधार पर विकसित करने हेतु शिक्षा का प्रसार करना चाहिये, ताकि इस उद्योग में लगे व्यक्ति मरलता से नये औजार व तौर-तरीके अपना सके। विकास विभाग को चाहिये कि वह इस उद्योग से सम्बन्धित फिल्में समय-समय पर गाँवों में दिखाये।

३ कुम्भकारों की छोटी-छोटी सहकारी समितियाँ बनाई जानी चाहिये, ताकि इस उद्योग में लगे व्यक्तियों को उचित ब्याज दर पर ऋण आदि प्राप्त हो सके तथा साथ ही साथ तैयार माल व्यवस्थित बाजारों व मेलों में लाभदायक कीमत पर बेचा जा सके।

बल्लभ विद्यानगर ५ अगस्त १९६३ —खेमराज पिछोलिया

अभिनव भेड़-पालन

भारत में ४० लाख भेड़ हैं, परन्तु उनसे जो ऊन तैयार होता है वह ४४ करोड़ लोगों की आवश्यकता की तुलना में बहुत ही कम है। निस्सन्देह भेड़ों की संख्या बढ़ा कर ऊन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तथापि, चन्द विदेशों में भेड़-पालन को नैदानिक तरीके अपना रहे हैं, जोकि ऊन उत्पादन में वृद्धि तो करते ही हैं, साथ ही ऊन के स्तर में भी सुधार करते हैं। यह आवश्यक है कि हमारे भेड़-पालक भी भेड़-पालन के वे तरीके अपनाये,

जिनसे वे ऊनी मिलों को ऊन की सप्लाई तथा प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। राष्ट्रीय सकटकाल का यह आवाहन है कि सभी स्रोतों का प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाय। बर्फीले हिमालय में देश की रक्षा के लिए जूझ रहे जवानों के ऊनी कपड़ों के लिए भारत अब आयातीत ऊन पर निर्भर नहीं कर सकता।

प्रश्न उठता है कि ऊन उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक हल यह है कि अच्छी भेड़ों का चयन किया जाय,

जिनका सभी बदन ऊन से भरा हो यानी सम्पूर्ण शरीर पर ऊन हो और वह भी लम्बा, कोमल तथा सतोषजनक वजन का हो। इस प्रकार की भेड़ों से प्रजनन कराने से ऊन का उत्पादन बढ़ेगा। बारिग, सूखा और जहाँ-तहाँ चरने देने के कारण भेड़ का स्वास्थ्य गिरता है और फलतः उसका ऊन उत्पादन पर भी असर पड़ता है। यदि विवेकपूर्ण ढंग से भेड़ को स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा चरने के लिए नित्य बारह घण्टे छोड़ दिया जाय तो इस समस्या का हल हो सकता है।

अन्दर के परजीवी अप्रत्यक्ष रूप से और बाहर के परजीवी प्रत्यक्ष रूप से ऊन को बढ़ने देने से रोकते हैं। टिक, जुएँ, पिस्सू, खुजली के कीड़े आदि चर्म-कोठों पर पलते हैं, जोकि ऊन के पैदा होने की जड़े हैं। परन्तु ये

परजीवि उन पौष्टिक तत्वों को खा जाते हैं, जोकि ऊन की बाढ के लिए हैं। वे चमड़े में खूजलाहट पैदा करते हैं और उससे किरैटिनीकरण हो जाता है, जिसका फल यह होता है कि ऊनी रेशे मोटे और खुरदरे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भेड़ को १५-२० दिन तक 'डिपिंग सोल्यूशन' में रखना चाहिये, ताकि उन्हें कोई महामारी न हो।

फिर, भेड़ से ऊन एक ही बार में चमड़े से बिल्कुल सटा कर उतारना चाहिये, परन्तु चमड़ा कटना नहीं चाहिये। ऐसा मौसम परिवर्तन के समय साल में दो बार करना चाहिये। ऊन में बाहरी बीजे नहीं मिलने देनी चाहिये। भेड़ को बहते सोते में नहाने से ऊन चमकीला और आनम्य होता है।

बनजार (कुलू) १४ मई १९६१

— गुलजार सिंह

कश्मीरी 'गब्बे' की कहानी

कश्मीर की भौगोलिक स्थिति और शीतल जलवायु ऐसी है कि प्राचीन युग से ही वह ऊन और ऊनी उत्पादनों का गढ़ रहा है। ससार प्रसिद्ध कश्मीरी शाल कलात्मक और आकर्षक होने के साथ ही ठंड से भी काफी बचाव करता है। रंग-विरंगी डिजाइनवाली कश्मीरी कालीने देश-विदेश के अमीरों के घर सजाती रही हैं। तथापि, कश्मीरियों ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया है। वहाँ के ऊनी टवीड, घर में काते गये सूत से तैयार पट्टू और भारी परन्तु गर्म कम्बलों ने न सिर्फ घाटी के लोगों के लिए, बल्कि आस-पास के आम लोगों के लिए भी सस्ता वस्त्र प्रदान किया है। इसी प्रकार मध्यम वर्ग के लोगों की कुटियों भी सस्ती परन्तु कलात्मक 'गब्बा' नामक कालीन से सुसज्जित हैं। प्रायः ये गब्बे गद्दे के तौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं, जिनमें धागे डाल कर रेखाएँ बनी रहती हैं तथा अन्दर रूई भरी होती हैं।

गब्बा तैयार करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। शहरो और गाँवों के घर-घर से प्राप्त पुराने कम्बलों और इस्तेमाल किये गये पट्टू वस्त्र को सावधानीपूर्वक

धोकर चमकीले और तेज रंग में रंग देते हैं। फिर उन्हें एक निश्चित डिजाइन के अनुसार छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और ज्यामितिक आकार में सिल देते हैं। किनारों के जोड़ों में हुकनुमा कशीदाकारी कर देते हैं और तब वह बिन्नी के लिए तैयार हो जाता है। सस्ते किस्म के गब्बे भी होते हैं। पुराने टुकड़ों को मिलाकर आवश्यकता-नुसार एक बड़ा टुकड़ा सिल देते हैं और फिर उसे एक रंग में रंग देते हैं। इस पर सब जगह हुक कशीदाकारी कर देते हैं अथवा छोट छाप देते हैं। कशीदाकारी में तरह-तरह की डिजाइनें बनायी जाती हैं, जिनमें प्रचलित हैं चेनार के पत्ते, आइरिस और तिब्बती ड्रैगन।

उद्गम

गब्बे का उद्गम अभी तक रहस्यमय ही बना हुआ है। बुजुर्गों से यह जानकारी मिलती है कि काबुल से आया एक शरणार्थी अब्दुल रहमान बाल कमल भट (कश्मीर में) के साथ रहता था और उसने अपने मेजबान के लिए कशीदा निकाल कर घोंडे की जीन का आवरण तैयार किया जिसे कि उसने बहुत पसन्द किया और धीरे-धीरे वह उद्योग के

बाद के विकास का स्वरूप हो गयी। एक मास्टर कारीगर की यह कहानी प्रसिद्ध है कि उसे 'खातमबन्द' नामक लकड़ी की छत्तो से प्रेरणा मिली, जिसमें कि लकड़ी के छोटे टुकड़ों को मिला कर ज्यामितिक आकार दिया जाता था। जडा वस्त्रों के लिए, जिसे कि मुसलमान फकीर पहनते हैं तथा जिनमें कुछ चिप्पी काम (पैच वर्क) भी करना पड़ता है, कुछ अधविश्वास भी व्याप्त है। गब्बा ऊन के वस्त्र का चिप्पी काम है और इसी कारण इसे लोकप्रियता भी मिली है। तथापि, एक मत यह भी है कि यह उद्योग डेढ़-सौ वर्ष से अधिक पुराना नहीं है।

प्रारम्भ में गब्बे की सिलाई मुख्यतः जमींदारों और जेलदारों के लिए की जाती थी, जोकि यद्यपि खर्चिले कालीन नहीं रख सकते थे, परन्तु अपनी मर्यादा बनाये रखने के लिए फर्श पर गब्बा बिछाया करते थे। महाराजा रणवीर सिंह के शासन-काल में इस उद्योग ने काफी प्रगति की। कुशल कारीगरों की सेवा प्राप्त छोटे कारखाने शाल और कालीन उत्पादन गृहों की तरह ही खोले गये। महाराजा स्वयम् अपने तथा अपने दरबारियों आदि के लिए बड़े-बड़े तम्बू बनवाया करते थे, जिनमें जडाऊ काम किया जाता था और रेशमी धागे से कशीदा निकाला जात था। इससे उद्योग को प्रोत्साहन मिला।

कश्मीर घूमनेवाले भ्रमणार्थियों की सख्या बढ़ने जाने से बिक्री बढ़ने लगी और निर्यात भी। परन्तु इससे गुण-स्तर में थोड़ी गिरावट आयी। सस्ते 'एनिलिन' रंगों, फटे-पुराने ऊनी पट्टू और कम्बलो तथा कशीदाकारी के लिए सूती धागे का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे स्वभावतः उद्योग में अवनति हुई और वह समाप्त प्राय हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के समय गब्बा उद्योग को नव जीवन प्राप्त हुआ। उस वक्त सस्ती कालीनों की बड़ी मांग थी और उनकी कीमते भी बहुत बढ़ गयी थी। सन् १९४६

में दो लाख रुपये का माल बेचा गया। गब्बा के निर्माण में उत्तम कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करने से भारत के बहुत-से घरों में इसका उपयोग उपस्कर (फर्नीचर) के अग स्वरूप दिनो-दिन बढ़ता गया। अनुमान है कि अभी इस उद्योग में एक हजार से अधिक व्यक्ति रोजगारी पा रहे हैं और वे सालाना तीन लाख रुपये के गब्बे तैयार करते हैं। श्रीनगर से ३४ मील दक्षिण में बसा अनन्तनाग इस उद्योग का मुख्य केन्द्र है। कुशल दस्तकार अधिकतर यहीं बसे हुए हैं और उनमें यह कला वशानुगत रूप में फलती-फूलती चली आ रही है। आस पास के गाँवों में घटिया किस्म के गब्बे तैयार किये जाते हैं।

घर-घर में लोकप्रिय

गब्बा निर्माण एक कुटीरोद्योग है। मास्टर कारीगर इस काम को अपने परिवार के सदस्यों तथा पारिश्रमिक पर काम करनेवाले चन्द अन्य कारीगरों की सहायता से अपने धंधे के रूप चलाता है। यह न सिर्फ एक निर्माण इकाई है, बल्कि यहाँ नवागतुक्त को प्रशिक्षण भी मिलता है। ये छोटी-छोटी इकाइयाँ ही गब्बा उत्पादन के एक बड़े भाग के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, हाल ही में आधुनिक पद्धति के बड़े कार्यगृह श्रीनगर में खोले गये हैं, जहाँ कि मशीन द्वारा रंगाई और सिलाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। राज्य सरकार के सहकार विभाग ने अनन्तनाग में सहकारी आधार पर उत्पादन कार्य संगठित किया है।

गब्बा दिनो-दिन अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। हाल ही में, उन्नत टाट के कपड़े तथा घनी कशीदाकारी के गब्बे लोगों में बहुत प्रचलित हो रहे हैं। राज्य बिक्री भवन, केन्द्रीय बाजार संगठनों और व्यापार माध्यमों की मदद से गब्बों की माँग में काफी वृद्धि हुई है। कश्मीर का यह प्राचीन उद्योग भविष्य में पनपनेगा ही। चण्डीगढ़ २६ दिसम्बर १९६३ —इन्दर मो भटनागर

सम्पादक सुभाष चन्द्र सत्कार द्वारा खादी और प्रामोद्योग कमीशन के लिए 'ग्रामोद्योग' इला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-९६ से प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल एसोसिएटेड प्रिन्टर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ९०९, तारदेव, आर्धर रोड, बम्बई-२४। वार्षिक छुल्क २ ५० रुपये, एक प्रति २५ पैसे।

दशम वर्ष • जुलाई १९६४ • दशम अंक



	पृष्ठ
नीरा बनाम ताडी	-वैकुण्ठ ल. मेहता ६४७
यगोस्त्राविया मे कृषि	-मिलम आयवनोविक ६५०
कागज की पारिमापिक स्थिरता	-ग. ह. गोंधलेकर ६५४
टीका-टिप्पणी	६५८
पचायत राज के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन	-हबीबुर रहमान ६६०
मैसूर के दो गाँवों मे कर्जदारी	-वन्दार वेकण्ण शेट्टी ६६३
जम्मू और कश्मीर मे रेशम उत्पादन का विकास	-मारवन लाल श्रट ६६९
ऊनी और पशम वस्त्रों मे सुधार के लिए भेड-पालन	-जेकल श्रीरामुलू पैट्रो ६७९
स्कूली बच्चों के विकास पर ताड-गुड का प्रभाव	-मेरी जार्ज ६८४
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सहकारिता प्रशासन	६९०
विस्तार पद्धतियों का प्रयोग	-शोमसुन्दरम् शनमुगम् ६९७
गोबर गैस सयत्र एक अध्ययन	-एस. डी. तेजनारायण और राम मूर्ति ६९९
प्रचार की निरर्थकता	-शुभाष चन्द्र सरकार ७०२
सहकार पर वैकुण्ठभाई के विचार	-रतिलाल मेहता ७०६

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोदय', इर्ला, बम्बई-९६ से मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थशास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-९६ (ए एस) के पते पर भेजें। टेलीफोन नं. २७१३२९।

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिये - असिस्टेण्ट प्रकाशक ऑफिसर (कैश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-९६ (ए एस)।

इस अंक के लेखक

वैकुण्ठ लल्लूभाई मेहता	—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।
मिलम आयबनोविक	—फेडरल वाइस-सेक्रेटरी फार एग्रीकल्चर, बेलग्रेड, युगोस्लाविया ।
गजानन हरि गोखलेकर	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के हाथ कागज उद्योग निर्देशक ।
हबीबुर रहमान	—अलीगढ़ स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में लेक्चरर ।
धन्वार बेकप्प शेट्टी	—परियोजना मूल्यांकन अधिकारी, शिमोगा (मैसूर) ।
माखन लाल भट्ट	—वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) स्थित कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र में प्रवर (सीनियर) अनुसंधान सहायक ।
पेकल श्रीरामलू पेंद्रो	—बिडलापुर (पश्चिम बंगाल) स्थित बिडला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के डार्इंग मास्टर और सीनियर वीविंग ओवरसीयर ।
मेरी जार्ज	—रानीपेट (मद्रास) स्थित राजकीय जूनियर एंग्रूड स्कूल में अनुसंधान सहायक ।
सोमसुन्दरम् शनमुगम्	—राजेन्द्रनगर (हैदराबाद) स्थित विस्तार अधिकारियों (उद्योग) के खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में लेक्चरर ।
एस. डी. तेजनारायण	—राजेन्द्रनगर (हैदराबाद) स्थित भारत सरकार के ओरियण्टेशन एण्ड स्टडी सेटर के भूतपूर्व प्राचार्य ।
राम मूर्ति	—नासिक स्थित खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में लेक्चरर ।
सुभाष चन्द्र सरकार	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग और जागृति के सम्पादक ।
रतिलाल महेता	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के प्रचार निर्देशालय में सहायक सम्पादक ।

नीरा बनाम ताड़ी

वैकुण्ठ ल. मेहता

एकसम नियमों और लाइसेंस-पद्धति के आधार पर तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलो द्वारा सहायित व मार्गदर्शित कारीगरों की सहकारी समितियों एवम् उनके सघों के जरिये नीरा और उससे सम्बन्धित उद्योगों का विकास करने से मद्यनिषेध नीति के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलेगी।

मद्यनिषेध अध्ययन दल का प्रतिवेदन एक बहुत ही मूल्यवान प्रलेख है, जिसमें उस विवादास्पद विषय पर प्रशासनीय ढंग से विचार किया गया है जोकि पिछले कई वर्षों से प्रशासकों और सामाजिक विचारकों के लिए एक पेचीदा सवाल बना हुआ है। मद्यपान का शायद ही कोई ऐसा पक्ष होगा, जिस पर अध्ययन दल ने विचार न किया हो। निष्कर्ष निकालने के पूर्व काफी अनुसंधान और तथ्यों का संग्रह किया गया है।

जिन विषयों पर विचार किया गया है, स्वभावतः उनमें एक विषय विभिन्न किस्म के ताड़-वृक्षों से प्राप्त नशीले पेय पर नियंत्रण भी है। इस प्रतिवेदन में एक अध्याय है "ताड़ी और नीरा की समस्या", जिसमें इन बातों से अवगत कराया गया है मद्यनिषेध और गैर-शराबबन्दीवाले क्षेत्रों की वर्तमान अवस्था, किस हालत में पेड़ों का छेदन किया जाता है, नीरा को ताड़ी का रूप लेने अर्थात् उसके खाद्य-तत्व में खमीर पैदा होने के पूर्व ही किस प्रकार खपाया जा सकता है, नीरा और ताड़-गुड़ उद्योग की गुंजाइश। उसके बाद प्रतिवेदन के मद्यनिषेध नीति के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावों-वाले अनुभाग के 'ताड़ी-नियमों में ढिलाई का प्रश्न' विषयक अध्याय में अध्ययन दल ने गुजरात और मद्रास को छोड़ कर देश के बाकी सभी हिस्सों में ताड़ी के उत्पादन और बिक्री पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने अथवा शर्तें निर्धारित करने के सुझाव दिये हैं।

ताड़ी की खपत

अध्ययन दल को आशा है कि यदि उसकी सिफारिश के अनुसार नीति अपनायी गयी तो दस-पन्द्रह वर्ष के

अन्दर ताड़ी-सेवन का परिपूर्णत निषेध करना सम्भव हो सकेगा। ताड़ी के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि इस पेय में मादक तत्व कम है और प्रतिवेदन में बताये अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करने पर इसके सेवन से होनेवाले नुकसान को बहुत ही सीमित किया जा सकता है। आज के बच्चे इस वातावरण में पलेगे कि शराब पीने की आदत को नागवार समझा जायगा। निर्धारित की जानेवाली सीमाओं पर बिना विस्तार में चर्चा किये, यह सन्देह प्रकट किया जा सकता है कि मद्यनिषेध को सफल बनाने में ये प्रस्तावित उपाय कितने प्रभावी सिद्ध होंगे, विशेषकर उन क्षेत्रों में—प्रायः जो दुर्गम हैं—जहाँ ताड़ वृक्षों का बाहुल्य है और जहाँ उन्हें सहज ही छेदा जा सकता है।

इन्हीं आशकाओं के कारण स्वराज आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में महात्मा गांधी ने लोगों को सस्ते में और सहज ही प्राप्य मद्य से बचाने के एक उपाय स्वरूप ताड़ी देनेवाले सभी वृक्षों को पूर्णतः नष्ट कर देने की बात कही थी। परन्तु जब गांधीजी ने बंगाल, मद्रास और केरल में ताड़-गुड़ उद्योग के कार्य और स्वरूप को देखा, तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उन्हीं के कहने से अखिल भारत ग्रामोद्योग सघ के कार्यक्रम में ताड़-गुड़ उद्योग के विकास को भी शामिल किया गया। स्वास्थ्यवर्धक पेय नीरा को कार्यक्रम के एक अग स्वरूप अपनाया गया। श्री जे. सी. कुमारप्पा ने वृक्षों को काट डालने के बदले और वृक्ष लगाने का आग्रह किया, ताकि

गन्ने की खेती में जितनी जमीन लगी है उसे कम किया जा सके।

अध्ययन दल ने ताड़-गुड़ उद्योग के विस्तार की सम्भावना को स्वीकार कर लिया है, अतः यहाँ इसका जिक्र करने का उद्देश्य वह मार्ग निर्दिष्ट करना है जिसका मद्यपान की बुराइयों को दूर करने के लिए सोच-समझ कर बनाये गये क्रमिक कार्यक्रम के कार्यान्वय हेतु अनुसरण किया जा सके। देश भर में विभिन्न किस्मों के ताड़-वृक्षों का छेदन स्वादिष्ट और पौष्टिक नीरा की पूर्ति करने और उपयुक्त संरक्षण के साथ पेय रूप में उसकी बिक्री एवम् खपत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना बनानी है। चूँकि नीरा खपत को प्रोत्साहन देने के बाद भी जो शर्तें रखी गयी हैं—और ठीक ही हैं—उनका पालन करते हुए हो सकता है कि उपलब्ध सारी नीरा की बिक्री की व्यवस्था न की जा सके, अतः बिक्री से बची नीरा से, उसमें खमीर पैदा होने के पूर्व ही, गुड़ और चीनी अथवा वातित पेय, शर्बत, जेली आदि बनाने की दिशा में जोरदार प्रयास करने चाहिये।

संरक्षण आवश्यक

ताड़ी के सम्बन्ध में अध्ययन दल की एक सिफारिश यह है कि जहाँ कहीं सम्भव हो वहाँ सरकार को चाहिये कि ताड़ी का उत्पादन और बिक्री वह अपने हाथ में ले ले। उसके ऐसा करने पर भी, यदि ताड़ छेदन के लिए जो छूट दी गयी है उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं होने देना है तो और भी कई संरक्षणात्मक उपायों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। अगर सरकार इस काम को स्वयम् नहीं चलाने का निर्णय करती है तो दूर-दूर के केन्द्रों के पर्यवेक्षण का कार्य इतना बड़ा होगा कि उसके लिए बड़े सरकारी खर्च पर विशेष निरीक्षण कर्मचारियों की बहाली की जरूरत पड़ेगी। इसकी तुलना में नीरा और ताड़-गुड़ उद्योग के विस्तार में कम कठिनाइयाँ आयेंगी।

सुविधाओं का दुरुपयोग ?

यद्यपि अध्ययन दल नीरा की पौष्टिकता को स्वीकार करता है तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्रम के अग स्वरूप काम कर रहे दहाणू स्थित भारतीय ताड़-

गुड़ शिल्प भवन के कार्यों की प्रशंसा करता है, दुर्भाग्य-वश उसने स्पष्टतः अखिल भारत योजना के अग स्वरूप ताड़ी के विकल्प रूप में नीरा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। कुछ हद तक उसका दृष्टिकोण देश के कुछ भागों से, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश व मैसूर से, प्राप्त नीरा और ताड़-गुड़ योजना के कार्यान्वय सम्बन्धी चन्द प्रतिवेदनो से प्रभावित है। गुजरात और मद्रास में, जिन्हें कि अध्ययन दल ने अपनी “ताड़ी नियमों में ढिलाई” योजना में शामिल न करने की सिफारिश की है, सहकारी समितियों अथवा समाज कल्याण अभिकरणों को नीरा प्राप्त करने हेतु ताड़-वृक्षों के छेदन की जो सुविधाएँ दी गयी हैं उनके दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं मिली है। मद्रास में सहकारी समितियों की संख्या बहुत है तथा उनके जिला सच होने के साथ ही एक राज्य स्तरीय शीर्ष उच्चस्थ सच भी है। महाराष्ट्र में भी, जहाँ मद्यनिषेध नीति में हाल ही में कुछ परिवर्तन हुआ है, इस उद्योग में लगी सहकारी समितियों को प्राप्त सुविधाओं के दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है, जिनके मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की है। और न ही इस बात का कोई प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ कि ताड़-गुड़ एक विकसित उद्योग है, नीरा का गैर-कानूनी उपयोग किया जाता है।

नीरा का परिरक्षण

ऐसा प्रतीत होता है कि अध्ययन दल को इस बात ने अधिक प्रभावित किया है कि नीरा ताड़ी से अधिक लोकप्रिय नहीं है। यह सम्भवतः उस क्षेत्र की बात है जहाँ मद्यनिषेध नहीं है। पर मद्यनिषेध लागू करने के लिए इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के बदले निरुत्साहित करना वाछनीय है। एक तीसरी बात, जिसे अध्ययन दल महत्व देता है, यह है कि नीरा इकट्ठी करने के लिए बर्तनों पर जो चूने की परत चढ़ायी जाती है, उसका बुरा असर पड़ता बताया जाता है। लेकिन यह पद्धति प्रमुख चिकित्सकों की स्वीकृति के बाद अप्रनायी गयी

नीरा बनाम ताड़ी

है, जोकि चूने का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकार नहीं समझते। इससे परिशोधन में अधिक खर्च नहीं पड़ता और काफी समय तक खमीर भी नहीं पैदा हो पाता, बशर्ते कि स्वास्थ्यकर वातावरण सुनिश्चित रहे, उपयुक्त ढग से उसका सग्रह हो और दूर-दूर तक ले जाने के लिए बर्फ डाली जा सकनेवाले बर्तनों का इस्तेमाल किया जाय। बम्बई, पुना और सूरत जैसे स्थानों में नीरा कार्य के अनुभव यह दर्शाते हैं कि सग्रह और परिवहन पर उपयुक्त नियंत्रण रहे तो नीरा आधे दिन तक तो परिरक्षित रखी ही जा सकती है।

उत्तम विकल्प

यदि अध्ययन दल के लिए ताड़ी के विकल्प रूप नीरा के प्रत्येक व्यावहारिक पक्ष का हर दृष्टि से मूल्यांकन करना सम्भव हो पाता तो यह निश्चित है कि उसमें खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा नियुक्त प्रशासकों और समाजसेवियों की समिति द्वारा हाल ही में नीरा और सम्बन्धित उद्योगों के लिए एक-सम नीति बनाने के लिए किये गये आग्रह का समर्थन किया होता। इस समिति ने सारे देश के लिए एक समान नियम और

लाइसेंस पद्धति बनाने का आग्रह किया है, ताकि जन-स्वास्थ्य सुधार, अधिक लोगों को रोजगारी देने और मिट्टी से सोने का निर्माण करते हुए राष्ट्रीय उत्पादन सृद्धि करने के हित में उद्योग का विकास करने में सुविधा हो अर्थात् मदद मिले। मद्यिक-तत्ववाली ताड़ी का पेय के रूप में इस्तेमाल किये जाने के प्रस्ताव से, जिसका कि टेकचन्द दल ने समर्थन किया है, जो भार बढ़नेवाला है, समिति द्वारा सुझाये गये उपाय को अमल में लाने से उससे अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। तथापि, कार्यक्रम के कार्यान्वय की जिम्मेवारी राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों द्वारा मार्गदर्शित और सहायित कारीगरों की सहकारी समितियों व उसके सघों को सौंपी जानी चाहिये। जैसाकि महात्मा गांधी ने वर्षों पूर्व ही यह भास कर लिया था कि इसी तरह के कार्यक्रम के जरिये हम असह्य ताड़-वृक्षों का सही उपयोग कर सकते हैं, गाँवों में लोगों को रोजगारी दे सकते हैं और एक पौष्टिक, स्वादिष्ट तथा सस्ते पेय की पूर्ति कर सकते हैं।

पुना . १७ जून १९६४

आम आय-कर दाताओं के घंघों पर आधारित आय-कर आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि १९५१-५६ की अवधि में टेकेदारों की औसत आय में सबसे अधिक वृद्धि हुई, इस वर्ग की आय में हुई वृद्धि देश के रोजगार प्राप्त लोगों की प्रति व्यक्ति आय-वृद्धि से बहुत अधिक है। आय-कर दाताओं में उन्ने घरे (निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्तीय व्यापार) में रोजगारी पा रहे लोगों तथा वेतनभोगियों की आय में भी वृद्धि हुई है, परन्तु उनके मामले में आय-वृद्धि की दर रोजगार-प्राप्त लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय दर के समान ही रही है।

—रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड लेवल्ल ऑफ लिविंग, पार्ट १ (डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ एण्ड कंसेप्टेशन ऑफ इकनॉमिक पावर)

युगोस्लाविया में कृषि

मिलम आयवनोविक

यद्यपि युगोस्लाविया की अर्थ-व्यवस्था में अब भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, तथापि पिछले पन्द्रह वर्ष में, अपने जीविकोपार्जन के लिए मात्र कृषि पर ही निर्भर करनेवाली जन-संख्या के प्रातिशत्य में कमी हुई है और राष्ट्रीय आय में उद्योग विभाग से होनेवाली आय का हिस्सा बढ़ा है। कृषि उत्पादन की वृद्धि में कृषि सहाकारी समितियों ने महान् भूमिका अदा की है। कृषि का यान्त्रीकरण बढ़ा तीव्र रहा है।

युगोस्लाविया की कृषि में १९५६ से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन उच्च उत्पादन वृद्धि उत्पादन-स्वरूप में अन्तर और बाजार सप्लाई के बुनियादी उत्पादकों के मध्य सम्बन्धों में विवर्तन में द्रष्टव्य हैं।

युगोस्लाविया की कृषि इस रूप में जानी जाती है कि उसमें पिछड़े कृषि-प्रधान देशों के कुछ गुण पाये जाते हैं, उदाहरणार्थ, खेतों का बहुत अधिक विभाजित होना, अपर्याप्त कृषिक यन्त्र, प्रति इकाई न्यून उत्पादन स्तर और न्यून उत्पादकता। तथापि, कृषि विकास के लिए अनुकूल मौके हैं, और, पिछले सात वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने द्रुत गति से उत्पादन बढ़ाना सम्भव बना दिया है। उदाहरण के लिए १९५२ से १९६० तक औसत वार्षिक उत्पादन वृद्धि ६१ प्रति शत रही है, जबकि १९५७ से १९६१ तक यही वृद्धि दर ७७ प्रति शत रही है। ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि प्रगति की प्रवृत्ति को मात्र एक लघु-कालीन और आकस्मिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता, जोकि प्राकृतिक अवस्थाओं, खास कर अनुकूल मौसम के कारण हो सकती है।

गैर खेतिहर धंधों का विकास

कृषि उत्पादन में द्रुत गति से वृद्धि करना जिन कारकों से सम्भव बन पड़ा है, उन पर विचार करना निश्चय ही रुचिकर होगा। सर्व प्रथम कारक है समग्र अर्थ-व्यवस्था का परिवर्तित संघटन। कृषि जब तक अर्थ-व्यवस्था की मुख्य शाखा रही, वह पिछड़ी हुई और

अल्पविकसित रही। प्रायः सभी विकासशील देशों में यह अवस्था पायी जाती है। लेकिन अन्य गैर खेतिहर कार्यशीलताओं के साथ उद्योग विकास के अर्थ-व्यवस्था का आधार बन जाने से कृषि के द्रुत विकास और उत्पादन के आधुनिक तौर-तरीकों का प्रयोग करने के लिए आर्थिक तथा तकनीकल अवस्थाएँ निर्मित हुईं।

उद्योग तथा अन्य गैर खेतिहर कार्यशीलताओं के विकास का सर्वोत्तम चित्र हमें आबादी की संघटना में हुए परिवर्तनों में मिलता है। सन् १९४८ में कुल आबादी में गैर खेतिहर आबादी २९६ प्रति शत थी। उसके तेरह वर्ष बाद अर्थात् १९६३ में उक्त प्रातिशत्य बढ़ कर ५०६ हो गया। अनुमान लगाया जाता है कि गैर खेतिहर और खेतिहर आबादी का प्रातिशत्य अब क्रमशः ५२५ तथा ४७५ है।

अन्य सूचक भी रुचिकर हैं। उनसे पता चलता है कि उद्योग का राष्ट्रीय आय में १९४७ में २४९ प्रति शत योगदान था और १९६३ में ४१२ प्रति शत, जबकि उसी वर्ष कृषि उत्पादन सामाजिक उत्पादन का मात्र २४ प्रति शत ही था। उद्योग और अन्य गैर खेतिहर गतिविधियों के विस्तार का कृषि विकास के अनुकूल अवस्थाओं पर बहुत अच्छा तथा कई तरह से प्रभाव पड़ा है। सर्व प्रथम, कृषि अतिरिक्त जन-संख्या से मुक्त हुई, द्वितीय, कृषि उत्पादनों के लिए सीधे उपभोग और प्रशोधन दोनों कामों के लिए ही सुस्थिर गति से माँग बढ़ी, और तृतीय, रफ़्तार-रफ़्तार कर के ऐसे उद्योगों का

विकास हुआ जोकि वे चीजे बनाते हैं, जिनके बिना आधुनिक कृषि की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह सच है कि अर्थ-व्यवस्था के अन्य अंगों के विकास की तुलना में यह पिछड़ी हुई है, और यह कि इसका उत्पादन विचरणशील है, जिसका सामान्यतः सतुलित आर्थिक विस्तार पर असर पड़ता है। इसके दूसरी ओर वृद्धिशील प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा जन-संख्या की घटना में परिवर्तनों के साथ श्रेष्ठ खाद्यान्नों की माँग बढ़ी है। तदनुसार, यद्यपि कृषि उत्पादन सात प्रति शत वार्षिक से भी ऊँची दर पर बढ़ रहा है, पर वह उपभोग की आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाता। इस प्रकार युगोस्लाविया मौस तथा मौस उत्पादनों का निर्यात करता है, लेकिन खाद्यान्नों का काफी परिमाण में आयात करता है। लेकिन अपनी प्राकृतिक अवस्थाओं, कृषि में लगे व्यक्तियों की संख्या और आर्थिक क्षेत्र की अन्य दिशाओं की प्रगति की दृष्टि से यह निश्चित है कि वह अन्ततोगत्वा कृषि उत्पादनों का भी महत्वपूर्ण निर्यातक बन जायेगा।

कृषि उत्पादन में प्रगति

सन् १९६३ के अन्त में केवल १२.४ प्रति शत कृष्य भूमि ही समाजवादी तथा सहकारी सगठनों के पास थी, जबकि शेष ८७.६ प्रति शत जमीन २६ लाख स्वतंत्र किसानों के पास थी, जिसका मतलब है कि निजी खेतों का औसत आकार ३.५ हेक्टर अथवा ८.५ एकड़ है। यदि हम यह कहें कि निजी किसान परिवार के पास ज्यादा से ज्यादा करीब २४ एकड़ के बराबर खेत हो सकता है, तो भी यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के किसानों की कृषिक उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बहुत न्यून है।

यह सर्वविदित है कि छोटे-छोटे निजी खेतों में उत्पादकता किसी एक सीमा तक ही बढ़ायी जा सकती है, और यह कि उस सीमा का स्तर बहुत नीचा होता है। इस प्रकार के छोटे खेतों के कारण किसानों को, यदि उनके पास अपने खेतों के सिवाय अतिरिक्त आय का अन्य कोई

जरिया नहीं है तो, गरीबी की हालत में रहना पड़ता है। यदि उन्हें कहीं आशिक काम मिल भी जाता है तो भी उनकी उत्पादकता, खेतों में व अन्यत्र, दोनों ही स्थानों में, बहुत कम होती है। विकसित तथा अविकसित दोनों ही प्रकार के देशों को आज इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निस्सन्देह युगोस्लाविया की अर्थ-व्यवस्था में महान सफलता प्राप्त की गयी है, वह यह कि १९४५ से अर्थात् गत महायुद्ध के बाद से लेकर खेतिहर आबादी का अनुपात बहुत अधिक घटा है—वह कुल आबादी के ७६ प्रति शत से घट कर ४७.५ प्रति शत हो गया है। चूँकि कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के अवसर अब भी सीमित हैं, इसलिए समाजिक-राजनीतिक उद्देश्यों, राष्ट्रीय आय में और वृद्धि होने तथा आर्थिक एवम् सामाजिक विकास और भी तीव्र गति से करने की आवश्यकता की दृष्टि से उस आबादी की आमदनी बढ़ाने के लिए जो आगे भी गैर-कृषि क्षेत्रों में नए-नए उपाय खोज निकालने पड़ेंगे। इन योग्य शरीरधारी खेतिहरों की—जिनकी संख्या काफी अधिक है—उत्पादकता बढ़ाने के लिए तीव्र-तरीकों की खोज करना भी परमावश्यक है।

सघन कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े-बड़े समाजवादी कृषिक सगठन बनाये गये हैं। कृषिक-औद्योगिक संस्थानों के रूप में इन सभी सगठनों के पास २० हजार हेक्टर जमीन है। ये सगठन उपयोग के लिए तैयार माल के रूप में खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं अथवा बाजार में आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति करते हैं। इसी आधार पर कृषिक सहकार बड़ी-बड़ी उत्पादन इकाइयों का रूप ले रहे हैं। इन दो प्रकार के सगठनों ने १९६३ में करीब १३ लाख हेक्टर भूमि पर काम किया। देश की कुल कृष्य भूमि का यह केवल १२.४ प्रति शत ही है लेकिन उनका उत्पादन कुल कृषि उत्पादन का १७ प्रति शत या बाजार में आये समग्र उत्पादन का ४० प्रति शत रहा। उन सगठनों ने बड़ी तेज गति से अपना उत्पादन बढ़ाया है। उन्होंने १९५६ से १९६३ तक अपनी जमीन में करीब ५० प्रति शत वृद्धि की और

कुल उत्पादन में लगभग ४५० प्रति शत। इन आँकड़ों से पता चलता है कि इन सगठनों ने पिछले सात वर्षों की अवधि में कृषि उत्पादन के विस्तार में कितनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है।

यांत्रिक कृषि

कृषिक सहकार विशिष्ट प्रकार के कृषिक सगठन है। विशिष्ट अवस्थाओं में उनका जन्म हुआ और वे विकसित हुए। युगोस्लाविया में उनकी एक लम्बी परम्परा है। इन सहकारों के प्रबन्ध को लोकतांत्रिक रूप दिया जा चुका है। निजी किसानों के साथ सहयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाना उनका मुख्य कार्य है। वे यंत्रों में विनियोजक बन गये हैं, जिनका निजी खेतों में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिससे वे निजी किसानों के खेतों (कुल के १५ प्रति शत क्षेत्र पर निजी किसानों की मालिकी है) में—जिनके साथ वे सहयोग करते हैं—कृषि के आधुनिक तौर-तरीकों का समावेश कर सके हैं। अभी तक यह बड़े-बड़े समाजवादी और सहकारी खेतों के समान मधन उत्पादन नहीं है, लेकिन यह एक तथ्य है कि उन किसानों की तुलना में जो अपने खेतों में अकेले काम करते हैं, उन किसानों के खेतों का उत्पादन ५० प्रति शत अधिक है, जो कृषिक सहकारों की सहायता से काम करते हैं। तदनुसार, निजी किसानों में यह सहकारिताएँ सहकार के प्रमुख सगठन बन गयी हैं, और यह कि ये ऐसे सगठन हैं जो अपने पास आवश्यक तंत्र होने की वजह से कृषि उत्पादन के विकास और उसके सामाजीकरण को प्रभावित करते हैं।

कृषिक उत्पादन में वृद्धि कृषिक सगठनों द्वारा उपयोग में लाये जानेवाले प्राविधिक उपकरणों में अधिक विनियोजन करने का फल है। मन् १९५७ से १९६३ तक कृषिक सगठनों में प्राविधिक उपकरणों पर परिव्यय अलग-अलग वर्षों में समग्र आर्थिक विनियोजन के १२.६ से लेकर २०.७ प्रति शत तक रहा है।

कृषि में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का समावेश करने की दिशा में खास कर बड़ी तेज प्रगति हुई है। अनेक

वर्षों तक यंत्रों पर कृषि के समग्र व्यय का ५० प्रति शत तक खर्च होता रहा है। यंत्र विस्तार का चित्र इन आँकड़ों से बिस्कुल स्पष्ट हो जाता है। कृषि सगठनों के पास १५,७०० ट्रैक्टर, ४,८०० उर्वरक यंत्र, ३,१०० हल, ६०० गेहूँ सयुक्त फसल कटाई यंत्र, १,६०० लौरी आदि थे। सन् १९६३ तक उन्होंने अपने यंत्रों के भण्डार में वृद्धि कर ली थी और उनके पास ३५,००० ट्रैक्टर, ६,००० उर्वरक छिडकक (स्प्रेयर), ७,८०० हल, ८,४०० सयुक्त फसल कटाई यंत्र, २,९०० लौरी आदि थे। यद्यपि इनने यंत्र भी पर्याप्त नहीं है, तथापि वृद्धि उल्लेखनीय है।

कृत्रिम उर्वरकों के उपभोग में वृद्धि तो और भी उल्लेखनीय है। सन् १९५५ में २ लाख ७२ हजार टन का उपभोग हुआ था और बढ़ते-बढ़ते १९५७ में वह ८ लाख ६ हजार टन, १९५९ में ११ लाख ४७ हजार टन, १९६१ में १० लाख ९० हजार टन तथा १९६३ में २१ लाख टन तक जा पहुँचा। अनुमान है कि इस वर्ष तकरीबन ३० लाख टन उर्वरकों का उपयोग होगा। कृत्रिम उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग समाजवादी सगठन और सहकारी समितियाँ, स्वतंत्र किसानों के साथ सहकार करते हुए करती है। इस वृद्धि के बावजूद अन्य देशों में उर्वरकों के प्रयोग की तुलना में यह उपभोग कम ही है। औसतन प्रति हेक्टर भूमि में ३०० किलोग्राम तक खाद अथवा करीब ६० किलोग्राम भूमि-सुधारक सामग्री का उपयोग होता है।

इसी प्रकार चुनिन्दा किस्म के बीजों के उपयोग और उच्च फल-प्राप्ति देनेवाली फसलें बोने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। गेहूँ की खेती के अन्तर्गत २१ लाख हेक्टर भूमि है, जिसके ६० प्रति शत पर उच्च उत्पादन देनेवाली किस्म की फसल पैदा की जाती है। कुल भूमि के करीब २५ प्रति शत अर्थात् २५ लाख हेक्टर पर मक्का की खेती होती है। बोआई के लिए प्रसकर बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्यमुखी की कृषि के अन्तर्गत प्रायः समग्र भूमि पर उच्च उत्पादक किस्में बोयी जाती हैं।

युगोस्लाविया में कृषि

सामाजिक मिल्कियतवाले बड़े-बड़े क्षेत्र बागवानी, फलोद्यान व अगुरोपवन के अन्तर्गत हैं। आधुनिकतम यंत्रों और उपकरणों का यहाँ उपयोग होता है। आगामी कुछ वर्षों में प्रायः ये सभी बगीचे और फलोद्यान फलने लगेंगे।

पशु-प्रजनन

पशु-प्रजनन की दिशा में भी अच्छे फल प्राप्त हुए हैं। होल्स्टेइन-फ्रीसींगन और रेड डेनिश नस्ल की दुधारू गायों के आयात से पुनर्प्रजनन केन्द्र खोलने में मदद मिली है। सामाजिक मिल्कियत के बड़े दुग्धालयों के लिए बड़े-बड़े शहरी केन्द्रों के आस-पास इन केन्द्रों ने पशु-प्रजनन का काम होता है। घरेलू सिमेंटल (Simental) प्रजाति के गुण-धर्म में सुधार करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है। यह प्रजाति दूध और माँस दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है।

देश की सिचाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी इसी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। अब तक केवल १ लाख ४० हजार हेक्टर भूमि को ही सिचाई के अन्तर्गत लाया जा सका है। डेन्यूब-टीसा-डेन्यूब जल-व्यवस्था (हायड्रो-सिस्टम) आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी है। इसके पूरी होने पर इससे आठ लाख हेक्टर पर जलोत्सर्जन और ३ लाख ६० हजार हेक्टर नये क्षेत्र की सिचाई होगी। फिलहाल मकदूनिया में छ जल-व्यवस्था योजनाओं का काम चल रहा है, जो करीब एक लाख हेक्टर पर जलोत्सर्जन करेगी और मकदूनियायी मैदानों में ७२ हजार हेक्टर भूमि की सिचाई।

कृषिक उत्पादन के प्राविधिक आधार के विकास को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तथापि, इसका वर्तमान स्तर बहुत नीचा है और आगामी सात वर्षीय अवधि के दौरान इसमें पर्याप्त सुधार लाया जाना चाहिये। सन् १९७० के अन्त में युगोस्लाविया की कृषि का कुछ अलग ही सघटन होगा, और उसमें तब सघनता भी अधिक होगी। उस वक्त विस्तृत भूमि में सामाजिक मिल्कियत के अन्तर्गत भूमि की आधुनिक तकनीकल साधनों से जोनाई होगी, और निजी किसानों से सहकार करते हुए खेतों की जानेवाले क्षेत्रों के उत्पादन में भी सुधार होगा। और, अन्त में कृषि पर आधुनिक तकनीकल साधनों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए पिछली दो पंच वर्षीय अवधियों के न्यूनतम और अधिकतम उत्पादन की तुलना करना लाभप्रद होगा।

तालिका १

न्यूनतम और अधिकतम उपज: १९५४-६३
(हजार टन में)

	१९५४-१९५८		१९५९-१९६३	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
गेहूँ	१,३८०	५,१००	३,१७०	४,१३०
मक्का	३,०००	५,६६०	४,५५०	६,६७०
चूकन्दर	१,१३०	२,०३०	१,७३०	२,७३०
सूर्यमुखी	५९	१२५	९८	२३७
तिपतिया				
घास	७५०	९६०	१,३३०	१,६८०

ऐसा कहा जाता है कि युगोस्लाविया में कृषि उत्पादकों की तीन श्रेणियों है। राष्ट्रीय अनुपातों में उनकी औसत उपज १९६२ के अत्यधिक बुरे वर्ष में इस प्रकार रही

तालिका २

प्रति हेक्टर उपज मेट्रिक विषण्टलो में

	परिपूर्ण सामाजिक मिल्कियत के खेत		निजी खेत	
	कुल	सामाजिक मिल्कियत के खेत	समाजवादी विभाग के सहकार में	स्वतंत्र
गेहूँ	१६५	२८९	१८४	१२५
मक्का	२१५	४४९	३०३	१५९
चूकन्दर	२५१०	२९८०	२१००	१८४४
सूर्यमुखी	१०८	२२८	१६४	९९
दूध उत्पादन				
क्षमता	१,०७८	२,२६०	९८०	

निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि कृषि के अपेक्षाकृत गतिशील विकास और उत्पादन स्तर को ऊपर उठाने से युगोस्लाविया की कृषि की समस्याएँ हल नहीं हो गयी हैं। कृषि उत्पादनों का अब भी काफी मात्रा में आयात होता है, यद्यपि वे देश में ही पैदा किये जा सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्ष में कृषि उत्पादनों का निर्यात बढ़ा है। लेकिन इसमें कोई गन्दह नहीं कि युगोस्लाविया अपनी प्राकृतिक जल-वायु और विवेकशील उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस स्तर पर निर्यात कर सकता है, उक्त उत्पादनों के निर्यात को अभी तक वह स्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

बेलग्रेड १२ मई १९६४

कागज की पारिमापिक स्थिरता*

ग. ह. गोंधलेकर

प्रस्तुत लेख में कागज की पारिमापिक स्थिरता को प्रभावित करनेवाले कारकों का विश्लेषण किया गया है। लेखक ने उन दिशाओं का भी सुझाव दिया है, जिनमें हाथ कागज की पारिमापिक स्थिरता पर काबू पाने हेतु प्रयास किये जा सकते हैं।

कागज की पारिमापिक स्थिरता (डायमेन्शनल स्टेबिलिटी) किसे कहते हैं? जहाँ तक इस लेख का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि कागज की पारिमापिक स्थिरता वह सीमा है जिस तक नमी की विभिन्न अवस्थाओं के अन्तर्गत कागज के परिमाण में अन्तर आता है। कागज के छपाई सम्बन्धी गुणों पर मुख्यतः इस प्रकार असर पड़ता है

१ पारिमापिक दृष्टि से अस्थिर कागज में सिलवटे पड़ जाती हैं और वह पिचक जाता है। वे बिल्कुल सपाट नहीं रहते तथा छापेखाने में मशीन पर अपने आप एक के बाद एक कागज जाते रहने की क्रिया में कठिनाई पैदा करते हैं।

२ बहु-रंगी काम में पारिमापिक दृष्टि से अस्थिर कागज ठीक से छपाई न होने का कारण बनता है। यह बात मुख्यतः बहु-रंगी छपाई के लिए सही है, लेकिन कुछ ऐसे अन्य कामों को भी यह प्रभावित कर सकती है, जहाँ कालम भर कर 'कारबन' प्रतियाँ निकाली जाती हैं। ये कालम एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे यानी सभी कागजों में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सिधाई में होने ही चाहिए।

कागज की पारिमापिक स्थिरता को प्रभावित करनेवाले कारक हैं (अ) तन्तु का गुण, (आ) लुग्दी तैयार करने का तरीका, (इ) बीटिंग, (ई) धुलाई

का तरीका, (उ) आर्द्र-मजबूती प्रदान करना (वेट स्ट्रेथनिंग), (ऊ) भरत, (ए) तन्तुओं का सघटन और अभिविन्यास, (ऐ) सुखावन के दौरान सिलवट का पड़ जाना, (ओ) सुखावन का तापमान, (औ) सुखावन के दरमियान तनाव, और (अ) कागज का अनुकूलन।

तालिका १ के अध्ययन से उक्त कारकों का प्रभाव स्पष्ट हो जायेगा।

तालिका १

तन्तु के गुण और लुग्दी बनाने का तरीका

कच्ची सामग्री व तरीका	आर्द्र विस्तार / आडी दिशा में
सूचिपर्ण काष्ठ सल्फाइट	३.८
रुद्विपर्ण काष्ठ सल्फाइट	२.२
तृण सोडा	४.२
बास सोडा	२.०
खोई सोडा	१.९
एस्पर्टो सोडा	१.३
तृण उष्ण दबाव सोडा	४.२
तृण मोनो सल्फाइट	३.८
तृण क्लोराइन सोडा प्रक्रिया	३.७
एस्पर्टो उष्ण सोडा	१.३
एस्पर्टो अखण्ड क्राफ्ट	१.३
एस्पर्टो पाण्डिया (उच्च प्राप्ति)	१.५

* यह लेख पूना स्थित हाथ कागज संस्था में स्थापित "टेक्नीकल डिस्कशन ग्रुप" की १५ अप्रैल १९६४ को सप्ताह बैठक में 'पेपर' के रूप में पढ़ा गया था।

यह देखा जा सकता है कि तन्तु के गुण-धर्म का बहुत प्रभाव पड़ता है। विशेष दिलचस्पी की बात यह है कि वास, खोई और एस्पर्टो के मामले में विस्तार बहुत कम है। इसके विपरीत तृण-लुग्दी पर्याप्त अधिक विस्तारशील है।

पेषण (बीटिंग) का क्या असर पड़ता है, तालिका २ में प्रस्तुत आकड़ों से समझा जा सकता है।

तालिका २

पेषण (बीटिंग) का प्रभाव

कागज	आर्द्र विस्तार अपेक्षित	आर्द्र विस्तार ५० अंश एस आर तक पेषित
तृण उष्ण सोडा	४ २	५ ३
तृण मोनो सल्फाइट	३ ८	५ ०
तृण सोडा क्लोराइन	३ ७	४ ९
सूचिपर्ण काष्ठ सल्फाइट	३ ८	४ ८
रुन्दिपर्ण काष्ठ सल्फाइट	२ २	३ १
काष्ठ का बुरादा	१ ८	२ १
एस्पर्टो उष्ण सोडा	१ ३	२ १
एस्पर्टो अखण्ड क्राफ्ट	१ ४	२ ३
एस्पर्टो पाण्डिया	१ ४	२ २

यहाँ भी पेषण (बीटिंग) प्रभाव काष्ठ के बुरादे और एस्पर्टो के मामले में उतना ज्यादा नहीं है, जितना कि अन्य प्रकार की लुग्दी में।

धुलाई का तरीका

आधुनिक धुलाई छलनियों पर लुग्दी का लेप बत जाता है। इससे लुग्दी में की महीन-महीन सामग्री बह कर निकल नहीं पाती। इस कारण वह लुग्दी में ही रह जाती है।

एक मत के अनुसार पारिमापिक अस्थिरता का कारण यह है कि मूल तन्तु के हेमी-सेल्यूलोजिक पदार्थ

के फूलने से और अच्छी तरह पेषित लुग्दी के तन्तुकरण-कणों से आस-पास के तन्तुओं में गति पैदा होती है। एक दूसरा मत यह है कि स्वयम् तन्तुओं का फूलना ही विस्तार के लिए उत्तरदायी है।

आर्द्र मजबूती

कागज को आर्द्र मजबूती (यानी गीलेपन की अवस्था में भी कुछ रासायनिक द्रव्यों से उपचार करके कागज को मजबूती प्रदान करना, जिसे अंग्रेजी में 'वेट स्ट्रेन्थनिंग' कहते हैं) प्रदान करने का उसकी पारिमापिक स्थिरता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी, इसका प्रभाव बहुत कम होता है। यह भी हो सकता है कि यह प्रभाव परोक्ष रूप से कम पेषण करने से होता है, जोकि कभी-कभी आर्द्र-मजबूती प्रदायक कारक सम्भव बना देते हैं।

भरत

चीनी मिट्टी तथा अन्य खनिज भरतों से निश्चय ही कागज के सपाटपन और पारिमापिक स्थिरता में वृद्धि होती है। उक्त बात से सभी परिचित हैं। यह भी विदित है कि इससे कागज कमजोर भी पड़ता है। आर्द्रता ग्राही होने की वजह से ग्वार के गोंद जैसे पदार्थ भी किसी हद तक नमी में कमी होने से अत्यधिक सिकुड़न को रोकने में सहायक हो सकते हैं। इसी प्रकार सॉबिटाल से भी कागज में पर्याप्त नमी बनाये रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन जब 'लियो-ऑफसेट प्रिंटिंग' (एक प्रकार की छपाई) में वस्तुतः कागज को आर्द्र बनाया जाता है तब, खनिज भरतों के अलावा अन्य भरत हो सकता है विशेष उपयोगी न हो।

तंतु संघटन और अभिविन्यास

फोण्ड्रिनियर अथवा सिलीण्डर मोल्ड पर बने कागज में सीधी दिशा (मशीन डायरेक्शन) में तन्तुओं का अभिविन्यास काफी अधिक है। तनाव के साथ सुखाने—जिसका जिक्र हम आगे करेंगे—से उक्त कारक कागज का विभिन्न दिशाओं में अनिश्चित विस्तार कर देता

है। परिपूर्णत पानी में डूबे हुए कागज के विस्तार के सम्बन्ध में आकड़े इस प्रकार हैं

वृद्धि	प्रातिशत्य
लम्बाई में सीधी दिशा में	० ३
लम्बाई में आड़ी दिशा में	३ ०
मोटाई में	३० ०

यह ध्यान देने की बात है कि मोटाई में विस्तार सीधी दिशा (मशीन डायरेक्शन) विस्तार से १०० गुना ज्यादा है। इसका मतलब है अधिकांश वृद्धि मोटाई में होती है। आड़ी दिशा और मशीन दिशा में विस्तार मामूली होता है। इसलिए अगर किसी तरह यह व्यवस्था की जा सके कि सभी परिवर्तन मोटाई में हो तो सीधी और आड़ी दिशा में विष्कुल पारिभाषिक अस्थिरता नहीं रहेगी। वास्तव में मशीन से बने कागज के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, उसमें दोनों दिशाओं में असमान विस्तार का होना। यह एक सामान्य अनुभव है कि जो कागज सघटन में एक समान नहीं है (यहाँ तक कि हाथ कागज भी) उसे सपाट रखना मुश्किल होता है। आर्द्र मौसम में उसमें सिलवटे पड़ने लगती हैं।

सिकुड़न, तापमान और तनाव

मशीन बने कागज में सीधी दिशा में तनुओं के अभिविन्यास का प्रभाव सीधी दिशा में सिकुड़न पर लगायी जानेवाली रोक से और भी अधिक हो जाता है। कागज केवल आड़ी दिशा में ही मिकुड़ सकता है। और फिर, सुखाने के उच्च तापमान के कारण कागज में यह 'तनाव' सीधी दिशा में 'समाविष्ट' होता है एवम् वह तथाकथित 'सूखा हुआ तनाव' होता है।

यह बहुत अजीब बात है कि सुखाने के वक्त जिन तनावों का समावेश किया जाता है उनका स्थायी प्रभाव पड़े। अक्सर कागज को आड़ी दिशा की अपेक्षा सीधी दिशा में ही कम प्रसरण होने का स्मरण कैसे होता है? ऐसी किसी भी प्रक्रिया से जो इस स्मृति का लोप कर दे अथवा मिटा दे, कागज के ताव में इस प्रकार का

परिवर्तन सम्भव होना चाहिये कि दोनों ही दिशाओं में उसका समान विस्तार हो।

सुखाने के वक्त सिकुड़न का यह सवाल, स्वभावतः, तन्तु से नमी दूर करने से पड़नेवाले पृष्ठ-तनाव (सरफेस टेन्शन) के कारण, तन्तु बन्धन से सम्बद्ध है।

यदि मशीन कागज को आर्द्र किया जाय, आड़ी दिशा में ताना जाय और मामूली तनाव के साथ गर्मी दे कर सुखाया जाय तो कागज में से 'सूखे हुए खिचावों' में परिवर्तन करना सम्भव हो सकता है और नमी में परिवर्तनों के फलस्वरूप उसमें भविष्य में आड़ी दिशा में कम विस्तार होगा।

कागज अनुकूलन

एक अन्य महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण यह है कि कागज अनेक आर्द्रता चक्रों से गुजरने अथवा दीर्घ काल तक ६५ प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के अन्तर्गत रहने पर थोड़ा-सा सिकुड़ जाता है। एक बार सिकुड़न आ जाने पर वह समुचित रूप से स्थायी बन जाती है। यह बात मशीन से बने कागज के सम्बन्ध में खास तौर पर सही है, जिसे ऊष्मा प्रदान करके सुखाया जाता है और इसलिए वह आड़ी दिशा में अधिक सिकुड़ जाता है।

हाथ कागज उद्योग में

१ हाथ कागज में आड़ी और सीधी दिशाएँ नहीं होती। इसलिए दोनों ही दिशाओं में विस्तार समान होता है।

२ हाथ कागज हवा में सुखाये जाते हैं इसलिए उनमें बुरी तरह सिकुड़न पैदा हो जाती है। अतएव हाथ कागज में समस्या विस्तार की है। यह समस्या मशीन बने कागज के आड़ी दिशा में विस्तार की समस्या के समान है। लेकिन इस पर्यवेक्षण को कि खींचे हुए और ऊष्मा प्रदान कर सुखाये हुए कागज में कोई विशेष अस्थिरता नहीं होती, कागज के तावों में से पानी निकालते वक्त भारी दबाव डाल कर अपनाया जा सकता है।

३ इसी प्रकार पुनरावृत्त आर्द्रता और सुखावन से भी कागज को स्थिरता प्राप्त होती लगती है। सुखाने, माढी देने तथा पुन सुखाने व माढी देने की क्रिया करके हाथ कागज के सम्बन्ध में उक्त बात प्रयुक्त की जा सकती है। ऐसी कोशिश करके देखना अच्छा होगा।

४ पेषण (बीटिंग) की सीमा और तन्तु के गुण-धर्म पारिमापिक स्थिरता के लिए आंशिक रूप में उत्तरदायी है। यह परीक्षण करना लाभदायक रहेगा कि पेषण सीमा को कम करते हुए वांछित मजबूती किस तरह रखी जा सकती है। इस सम्बन्ध में 'सरेश माढी' के महत्व का निकट से अध्ययन करना वांछनीय है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में इंग्लिश हाथ कागज उद्योग एक रास्ता प्रशस्त करता है। वहाँ का तनु (लिण्टर) निम्न कोटि का है, लेकिन वहाँ 'सरेश माढी' की सीमा हमारी सरेश माढी की सीमा (लगभग पाच प्रति शत), की तुलना में बहुत अधिक (करीब १४ प्रति शत), है।

५ बास एक ऐसा तनु प्रदान करता है, जिसमें बेहतर पारिमापिक स्थिरता है। इसके उपयोग पर विचार करने की आवश्यकता है।

६ सुखावन के तापमान का स्थायी असर पड़ता है और वह 'सूखा हुआ खिचाव' पैदा करता है। चन्द मामलों में कागज ऊष्मा देकर, खास कर 'तावसुकी' की मदद लेकर, सुखाये जा सकते हैं।

७ जहाँ तक कागज के अनुकूलन का सवाल है, यह ध्यान देने की बात है कि उसका अनुकूलन छपाई के लिए काम में लायी जानेवाली आर्द्रता की अपेक्षा कम आर्द्रता की स्थिति में किया जाना वांछनीय है। इसका परिणाम यह निकलता है कि प्रथम रंगीन छपाई के दौरान जो अतिरिक्त नमी कागज में समा जाती है, दुबारा छपाई शुरू होने से पहले निकल जाती है।

यदि हाथ कागज को बाजार में अपना उपयुक्त प्राप्त स्थान करना है तो पारिमापिक स्थिरता का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उसका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है।

बम्बई १८ मई १९९४

सन्दर्भ

एफ. एल हडसन और एन जे हेन्सिस ब्रिटिश पेपर और बोर्ड मेकर्स एसोसिएशन के प्राविधिक विभाग की कार्यवाही, खण्ड ४०, भाग १, १९५९, डी आर कोल और एफ एल हडसन पेपर टेक्नोलॉजी, वर्ष २, अंक ५, १९५९, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के १९६२ में सपन्न एशिया और सुदूर पूर्व में लुग्दी तथा कागज विकास सम्बन्धी सम्मेलन की कार्यवाही में जे ग्रैण्ट की रचना यूज ऑफ शॉर्ट फायबर्ड पल्प इन प्रिंटिंग पेपर्स—छपाई के कागजों में छोटे तन्तुओं की लुग्दी का उपयोग।

भारत में मधुमक्खी-पालन

आपके लेख* में आपके कार्य का बड़ा ही रोचक विवरण है जोकि मधुमक्खी-पालन में रुचि लेनेवाले लोगों के लिए दिलचस्प है। हमारे सामने भी बहुत कुछ वैसी ही समस्याएँ हैं।

आपने भारतीय मधुमक्खी **एपिस इंडिका** का जो जिक्र किया है, मुझे अच्छा लगा। मैं मेथडिस्ट चर्च के अन्तर्गत एक शैक्षणिक मिशनरी के तौर पर २५ वर्षों तक चीन में रह चुका हूँ। वहाँ मैं जन्तुविज्ञान पढ़ाता था और साथ ही कृषि में विस्तार कार्य भी करता था। काफी समय तक मैंने **एपिस इंडिका** का प्रहस्तन और अध्ययन किया और चन्द प्रयोग भी। मैं हमेशा स्कूल में कई मधुमक्खी-घर रखता था और प्रायः गाँवों में यह देखने जाया करता था कि ग्रामीण किस तरह मधुमक्खी पालते हैं। मुझे यह बड़ा ही चित्ताकर्षक लगता था और मैंने इसका बहुत आनन्द उठाया।

आपने **इंडिका** का स्थान लेनेवाली मधुमक्खियों के आयात की सम्भावना का जिक्र किया है। जिन डाक्टर स्पेसर हँच का जिक्र आपने किया है, वे मेरे मित्र थे। जब वे भारत में थे तो हमारे बीच भारत में इतालियन मधुमक्खी लाने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हुआ और उन्होंने मुझे अपने आयातों के विषय में लिखा। बाद में मैं डा हँच से प्रथम बार मेक्सिको में मिला। वे वाय एम सी ए के लिए एक कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा बालकों के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न में थे। मैंने मधुमक्खी-पालन में उनकी सहायता की और उनके खले जाने के बाद कुछ समय तक मैं ही उनकी देख-भाल करता रहा। जब डा हँच कास्टा रीका में थे और छुट्टी पर जाना चाहते थे तो उन्होंने मुझे ९ महीने के लिए अपना काम सम्भालने हेतु निमन्त्रित किया और मैं वहाँ पहुँच गया। कोई एक साल पहले, उससे भी कुछ कम समय हुआ, वे गुजर गये।

जैसा कि आपने अपने लेख में बताया है मधुमक्खियों का आयात खतरनाक सिद्ध हो सकता है क्योंकि उनके

साथ ही नयी बीमारियाँ और परजीवि कीटाणु भी आ सकते हैं। अमेरिकी और यूरोपीय फाउल-ब्रूड (मधुमक्खियों की एक बीमारी) बीमारी सप्ताह में हर जगह फैली हुई है, अतः अगर मधुमक्खियों के आयात करने से सिर्फ उसी बीमारी का खतरा है तो कोई बात नहीं है। यदि पहले से ही वहाँ वह बीमारी हो तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई बीमारी नहीं है।

चीन में कोई फाउल-ब्रूड बीमारी नहीं थी। वहाँ के अपने २५ वर्ष के जीवन में जितने भी मधुमक्खी-घर मुझे मिले, मैंने सबको देखा, परन्तु मुझे कोई भी बीमारी-वाला मधु-घर नहीं मिला। क्या भारतीय मधुमक्खियों में उक्त फाउल-ब्रूड बीमारी मिलती है? इसका अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कोई ऐसी भी जगह है जहाँ कि यह बीमारी न हो।

चीन में १९२२ अथवा १९२३ के आस-पास मधुमक्खी-पालन के लिए लोगों में होड़ लगी हुई थी। जापान से (हो सकता है कि अन्य जगहों से भी) अनगिनत मधुमक्खियाँ जहाज के जरिये मगायी जा रही थी और अधिकांश मधुमक्खियाँ चीन के उत्तरी भाग में जा रही थी। परन्तु भेजनेवाले लापरवाह थे, इस कारण कुछ बैसे छत्ते भी आ गये जो फाउल-ब्रूड से पीड़ित थे। शीघ्र ही उत्तरीचीन के कई भागों में यह बीमारी फैल गयी। मुझे प्रथम बार यह बीमारी १९२५ में दक्षिण-पूर्व चीन के फ्यूकीन प्रांत में देखने को मिली— इतालियन मधुमक्खियों के सिर्फ एक छत्ते में यह बीमारी थी और वह छत्ता चीन के उत्तरी भाग से ही आया था।

मैंने अमेरिका से कुछ काकेशियन और इतालियन (बीमारी रहित) मधुमक्खियों का आयात किया और उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन बड़ा दिलचस्प रहा। चीनी मधुमक्खियाँ **एपिस इंडिका** इतालियन मधुमक्खियों के मुकाबले ठंडे मौसम में काम करती, हल्की बारिश में ज्यादा काम करती और सुबह में इतालियन मधुमक्खियों से भी पहले काम करने निकल जाती। उत्तर चीन में अनुभव यह रहा कि चीनी-मधुमक्खियों-

* "भारत में मधुमक्खी-पालन," छद्मनाम उन्मूलन सरकार, खादी ग्रामीणोद्योग, मार्च १९६४।

वाले क्षेत्र में इतालियन मधुमक्खियों के रख देने पर चीनी मधुमक्खियों धीरे-धीरे लुप्त होने लगी।

चीनी मधुमक्खियों सामान्यतया साल में ५ या ६ पौड, संभवतः ८ पौड भी, शहद देती थी, परन्तु जब मैंने एक छोटे आकार का मधुमक्खी-घर बनाया, जोकि लैंगस्ट्राथ आकार का तीन-चौथाई था, तो इंडिका छत्ते से ४० पौड शहद प्राप्त हुआ।

एपिश् इंडिका को अभी से और भी अच्छा काम करने के लिए चुना जा सकता है, परन्तु चुनाव में समय अधिक लगता है। इस बात के प्रमाण हैं कि आस्ट्रिया के मधु-पालक १८७९ में कई प्रदेशों को रानी-मक्खियों और अडे (नुकलिआई) बेचा करते थे। उन्हें शहद में दिल-चस्पी नहीं थी। वे सिर्फ मधुमक्खियों की बिक्री में ही रुचि रखते थे, इसलिए छोटे-छोटे मधु-घरों में मधुमक्खियाँ भर दिया करते थे और अब कानियोलन मधुमक्खियाँ इसके लिए मशहूर हो गयी हैं कि एक छत्ते में वे बहुत अधिक संख्या में रहती हैं। कुछ मधुमक्खी-पालक उस कारण उन्हें नहीं चाहते, परन्तु मैंने उन्हें पाल कर देखा है और मुझे वे बहुत पसन्द हैं। जहाजों में मधुमक्खियों भर-भर कर लाने का समय सन् १८७९ अंकित है, परन्तु चुनाव तो बहुत पहले से हो रहा था। हमारे लिए भारतीय अथवा चीनी मधुमक्खियों में सुधार करने से सस्ता पड़ेगा चुनिन्दा इतालियन अथवा काकेशियन या कानियोलन मधुमक्खियों का उपयोग करना। मैं अर्जेंटाइना के एक मधु-पालक से पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस तरह का मधुमक्खियों से काम आरम्भ किया, परन्तु कोई ५० वर्ष पहले उन्होंने इतालियन मधुमक्खियों का आयात किया और उन्हें अपनी मधुमक्खियों से अधिक उत्पादक पाया। तब मैं उन्हें काकेशियन मधुमक्खियों के बारे में लिखा करता था जिनका उन्होंने आयात किया और उन्हें इतालियन मधुमक्खियों से भी अच्छा पाया।

मधुमक्खी-पालन में मेरी रुचि शौकिया और वैज्ञानिक दृष्टि से है। व्यावसायिक मधुमक्खी-पालन में मेरा कोई अनुभव नहीं है। मेरे पास सिर्फ तीन छत्ते हैं और

मधुमक्खियाँ हैं काकेशियन। कनाडा में एक व्यक्ति दस वर्षों से उत्तम काकेशियन मधुमक्खियों का उत्पादन कर रहा है और मेरा विश्वास है कि उसके पास देश में उपलब्ध सर्वोत्तम नस्लों में से एक की मधुमक्खियाँ हैं। उसकी प्रजनक रानी मक्खियों की माँग आस्ट्रेलिया, पोलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका आदि में है और प्रति रानी-मक्खी उसे २० डॉलर (करीब १०० रुपये) मिलते हैं। पिछले वर्ष तो उसके पास इतनी माँग थी, जितनी मक्खियाँ उसके पास नहीं थी।

मेरे पास उसकी रानी-मक्खियों की नतिनियाँ हैं और मेरे पास अब तक की मधुमक्खियों में वे सर्वोत्तम हैं। श्री हेस्टिंग्स कैलिफोर्निया के एक मधु-पालक (जिसके पास विशुद्ध काकेशियन मधुमक्खियों का बागान है) को अपनी मधुमक्खियाँ बेचते हैं (तथा अन्य देशों के मधुमक्खी-पालकों को भी बेचते हैं) और उसके पास प्रजनक रानी मक्खियाँ हैं।^१ उसने अपने पास के ३ से ५ मील के अन्दर के सभी मधु-बागानों को रानी-मक्खियाँ दी हैं और इसलिए उसके बागान के आस-पास की सभी नर-मक्खियाँ विशुद्ध काकेशियन हैं। युवा रानी-मक्खियाँ समागम के बाद, १ ६० डॉलर में एक की दर से, बेच दी जाती हैं, और मैं वैसी ही रानी-मक्खियाँ खरीदता हूँ। वे बहुत अच्छी हैं।

मैं भारत में प्राप्त एपिश् इंडिका के विषय में और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या इन मधुमक्खियों के विषय में सरकार कोई प्रकाशन प्रसारित करती है? क्या एपिश् इंडिका पर किये गये अनुसंधान की जानकारी आपके पास उपलब्ध है? क्या किसी ने परजीवी कीटाणुओं का अध्ययन किया है? मैंने कहीं पढ़ा है कि भारत में एकादपिश् बूझाई मिला है। क्या भारत में नोसेमा एपिश् प्राप्य है? मुझे पता नहीं कि चीन में यह उपलब्ध है अथवा नहीं, परन्तु अमेरिका में तो है।

— क्लॉड आर. केलॉग

६५० वेस्ट हैरिसन एवेन्यू,
क्लेअरमोट, कैलिफोर्निया (स रा अ)
१५ जून १९६४

पंचायत राज के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन

हबीबुर रहमान

भारत के विकास में एक बाधा इस तथ्य के कारण है कि औद्योगिक क्रांति होने के पूर्व ही यहाँ राजनीतिक, सामाजिक और प्राविधिक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन नहीं हुए। लोगों की जीवन पद्धति और उनके विचार पर अब भी परम्परा हावी है। लोगों को जागरूक बनाने में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण से बहुत मदद मिल सकती है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया को देश की परम्परागत सामाजिक और आर्थिक रचना से अलग नहीं किया जा सकता। उससे अलग हो इसका अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर इसलिए है कि परम्परागत सिद्धान्त तथा वर्तमान आदर्श ब्रेमेल आर्थिक अथवा अर्द्ध यांत्रिक सम्बन्धों पर आधारित है, जोकि परम्परागत स्वरूप को एक देन तथा अनुकूल चीज मानते हैं। विश्लेषण करने से यह ज्ञात होगा कि सस्थात्मक सुधार के मामले में अबन्ध-नीति दर्शन न सिर्फ अव्यावहारिक, बल्कि गलत भी है। उत्पादन के तरीके में परिवर्तन से राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि धार्मिक पद्धतियों तक में परिवर्तन होता है, परन्तु अनुवर्ती में कोई परिवर्तन हो तो उनका प्रभाव पूर्ववर्ती पर भी पड़ता है।

संस्थात्मक स्वरूप और आर्थिक परिवर्तन

सस्थात्मक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तनों के 'अनुषंगिक प्रभाव' हो सकते हैं, परन्तु सस्थात्मक परिवर्तन भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे आर्थिक प्रभावों को समाप्त अथवा नियंत्रित कर सकते हैं। पूर्व-औद्योगिक और पूर्व-प्रौद्योगिक समाज की सस्थात्मक व्यवस्थाओं ने प्रायः आर्थिक विकास की गति में बाधा डाली है। प्राचीन और आधुनिक क्रिया के झगड़े के कारण, कम विकसित देशों में सामान्यतया और भारत में विशेषतया, परम्परा से लोग कुछ हट गये हैं। वेबलेन (Veblen) की यह धारणा कि सस्थात्मक परम्पराएँ सामाजिक

सुधारों को विकास की गति रोक और समाप्त कर मिलावटी बना देती हैं, हमारे देश के लिए तो सही है ही।

पश्चिम तथा सोवियत संघ में भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया के पहले अथवा बाद में दूरव्यापी सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। यूरोप में पुनरुद्भव और प्रोटेस्टेण्ट सुधारों ने लोगों की भावनाओं और धार्मिक शक्तियों को धर्मनिरपेक्ष कार्यों की ओर मोड़ा। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने एक नया जीवन प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप कट्टरपन, अधविश्वास और रीति-रिवाजों में बहुत अधिक विश्वास का स्थान प्रायोगिक और उपयोगितावादी किस्म के व्यवहारवादी परीक्षणों ने ले लिया।

स्वतंत्र व्यक्ति का प्रादुर्भाव

अतः यूरोप में बौद्धिक और आर्थिक विकास ने स्वतंत्र व्यक्ति को पैदा किया, जिसमें निष्ठापूर्वक और सोत्साहक काम करने, नियमितता बरतने तथा समय पर कार्य करने की भावना है, और जोकि धन उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त जनता का राजनीतिक रूप में एक होकर मजबूत केन्द्रीय और राष्ट्रीय राज्य के निर्माण, सर्फडम और गुलामी के अन्त तथा अवसरो की समानता ने गहरा प्रभाव डाला। जहाँ कहीं भी प्रतियोगात्मक प्रक्रिया असफल रही, वहाँ सरक्षणात्मक और सहकारी विधियों को अपनाया गया। सामाजिक विचार में कट्टरता को दूर करने

के लिए मनोवैज्ञानिक और आदर्शात्मक आन्दोलनों एवं व्यक्तिवादी दार्शनिक सिद्धान्तों ने एक नये यूरोप का निर्माण किया जोकि आधुनिक ज्ञान और तकनीकालाजी के उपयुक्त हो। इसका श्रेय लूथर, कॅल्विन (Calvin), गेलिलियो, न्यूटन आदि को है जिन्होंने कि परम्परा से बंधे समाज को एक प्राणवान और नव-संस्कृतियों को अपनानेवाले समाज में बदल डाला। भाषान्तरण और परिवर्तन की प्रक्रिया यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में भी जारी है।

परम्परागत समाज

परन्तु भारत में सामाजिक विकास की पद्धति ने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के उस पथ का अनुगमन नहीं किया जिससे होकर यूरोप औद्योगिक क्रांति के वक्त तथा उसके बाद गुजरा। पश्चिम में पहले जागरूकता आयी और तब हुआ विकास, परन्तु भारत में हम विकास के जरिये लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी राह में एक बाधा यह थी कि भारत में पश्चिम की तरह राजनीतिक, सामाजिक और प्राविधिक क्षेत्रों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, जोकि फलस्वरूप उसे बौद्धिक, कृषिक और औद्योगिक क्रांतियों के लिए तैयार कर सकता था। भारतीय समाज राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक सुधारों के बावजूद परम्पराबद्ध तथा वर्ग-मुखी रहा। संयुक्त परिवार, जातिवाद, 'समय-चक्र और नैसर्गिक-परिवर्तन' एवं 'विश्वास' सिद्धान्त ने विरक्ति, त्याग और अध-विश्वास को जन्म दिया। ये शक्तियाँ वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की विरोधी थी और इसलिए इन्होंने विकास की गति को रोकता तथा सरकार एवं जनता द्वारा उठाये गये क्रांतिकारी कदमों को धीमा कर दिया।

बाधक कारक

हम भारतीयों में से अधिकांश ने 'परम्परागत गुणों और पूर्वजों के सूक्ष्म दर्शन' को अधिक महत्व दिया। व्यापक भ्रमताधिकार ने जितनी समस्याओं का हल नहीं

किया, उससे अधिक समस्याएँ खड़ी कर दी, क्योंकि इमने जातिवाद और वर्गवाद को मजबूत बनाया जिससे कि विखंडित होने की ओर झुकाव बढ़ा। नेताओं के समर्थन, कानूनी उपायों और नये विचारों के बावजूद जनता आमूल सुधार अपनाने में हिचकती रही। संस्थाओं के श्रेणी-विभाजन, भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमियों और कार्यान्वयन में भाग न लेने के कारण भूमि सुधार के लिए किये गये उपाय बेकार हो गये। ये चीजें सही अनुशासन, अनुभव सिद्ध खोज तथा सामाजिक और भौतिक विकास के लिए ऐच्छिक एवं व्यक्तिगत पहल पैदा नहीं कर सकी। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जातिगत भावना, गतिहीन और भाग्यवादी रुख, अदक्ष जनशक्ति तथा पूँजी-स्रोत की कमीवाली हमारी अधर्मनिरपेक्ष और अप्राविधिक पद्धतिवाली संस्थाओं ने अधिक विकास को अवरुद्ध किया है।

पंचायत राज की भूमिका

भारतीय समाज के पुनर्नवीनीकरण हेतु आन्तरिक परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जिन परिवर्तनों को आम लोग चाहते हैं उन्हें समाज पर थोपे जानेवाले परिवर्तनों के बनिस्बत अधिक सहज समर्थन मिल जात है तथा कार्यान्वयन भी हो जाता है। कृषि उत्पादन वृद्धि तथा ग्राम निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की सेवा का आवश्यकता है, जिसे कि जनता को जागरूक बनाने बिना किसी संस्था की सहायता लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता। पंचायत राज सबसे महत्वपूर्ण मस्य है जोकि इस दिशा में सर्वाधिक योगदान दे सकती है ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए योजना आयोग भी ग्राम पंचायतों को ही उपयुक्त अभिकरण मानता है। राजस्थान में २ अक्टूबर १९५९ को पंचायत राज का उद्घाटन करते हुए ४ जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक क्रांतिकारी घटना कहा था, जिसका उद्देश्य जनता तक स्वराज पहुँचाना, उच्च स्वयं शासन चलाने में सहायता देना और पुनर्निर्माण

तथा विकास कार्यों के कार्यान्वय में दर्शक के बदले सजग कर्त्ता बनकर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मूल्यों में परिवर्तन

पचायत राज आन्दोलन के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि इसे पिछड़े, खडित और जाति-वृक्ष समाज का—जोकि पुरानी परम्पराएँ निभा रहा है और पुराने तरीके अपनाये हुए हैं—सामना करना है। इस तरह के समाज को न सिर्फ बुनियादी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की जरूरत है बल्कि एकीकृत और समन्वित समाज में परिवर्तित होने की भी आवश्यकता है, जिसमें जनता का उच्च जीवन-स्तर हो। और, इसके लिए अर्ध-सामन्तवादी और परम्परागत समाज को प्राविधिक रूप से चेतन समाज में न सिर्फ अच्छे, पुराने, ललित और नैतिक सिद्धान्तों को बनाये रखते हुए, बल्कि नये सामाजिक मूल्यों और सब समाज का स्वस्थ होने की भावना रखते हुए बदल देने की जरूरत है।

आज भारतीय गाँवों में ग्रामीणों की जीवन-पद्धति बदलने, नयी तकनीकों और विचारों के समावेश और ग्रामोद्योग के उपबुद्ध नयी संस्थाओं के निर्माण की

दृष्टि से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा आरम्भ किये गये कार्य चल रहे हैं।

यद्यपि पचायत चुनावों पर गाँव की शांति भग करने का दोष लगाया जाता है, तथापि वे उसे जागरूक और एक बनाने के लिए बड़े शक्तिशाली स्रोत सिद्ध हुए हैं। कई जगहों में तो सत्ता प्राप्त करने के लिए ही मही, ऊँची जात के लोगो ने निम्न जाति के लोगो के साथ समझौता किया है। इसके लिए ऊँची जातिवालों ने निम्न जातिवालों को कुछ रियायते दी हैं। राजनीतिक दलों ने ग्राम राजनीति में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन देते हुए भी परोक्ष रूप से उसमें भाग लिया है। अब तो शिक्षित युवक भी पचायती मामलों में भाग ले रहे हैं और कृषि के विकास तथा लघु उद्योगों की स्थापना में अपना योगदान दे रहे हैं। इन परिवर्तनों के जरिये जाति और सम्बन्धियों के प्रति बफादारी की जगह गाँव के प्रति बफादारी ले रही है, और भारतीय गाँवों की सामाजिक गति-हीनता का स्थान स्वावलम्बी और स्वशासित ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था ले रही है।

अलीगढ़ . १९ मई १९६४

भारत में १९५३-५४ और १९५९-६० वर्ष के जोत-वितरण की जानकारी के अनुसार आम तौर पर हमने यह पाया है कि मालिकी और कास्तकारी, दोनों ही किस्मों की जोत बहुत अधिक संकेद्रित हैं। वर्ष १९५३-५४ तथा १९५९-६० के बीच भूमि सुधार के कई तरीके अपनाये जाने के बाव भी असमानता में कोई खास कमी नहीं आयी। वर्ष १९५३-५४ में सर्वोच्च एक प्रति शत परिवारों के पास १७ प्रति शत, उच्च ५ प्रति शत के पास ४१ प्रति शत और उच्च १० प्रति शत परिवारों के पास ५८ प्रति शत मालिकी भूमि थी। वर्ष १९५९-६० में ये अनुपात क्रमशः १६ प्रति शत, ४० प्रति शत और ५६ प्रति शत थे। निम्न २० प्रति शत परिवारों के पास इन दोनों ही वर्षों में अपनी जमीन थी ही नहीं।

—रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड लेवल्स ऑफ लिविंग, पार्ट १ (डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ एण्ड कंसेंट्रेशन ऑफ इकनॉमिक पावर)

मैसूर के दो गाँवों में कर्जदारी

वन्दार वेंकप्प शेटी

प्रस्तुत लेख में मैसूर राज्य के दो गाँवों, हगरी बोम्मन्न हल्ली (ह बो हल्ली) और चित्रपल्ली का इस दृष्टि से अध्ययन किया गया है कि उनमें कर्जदारी कितनी और किस प्रकार की है तथा उधार लेनेवाले और देनेवाले अभिकरणों के विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं।

भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण

विशेषता यह है कि किसानों पर कर्ज का भार बहुत अधिक है। यह सर्व विदित है कि किस हद तक किसान साहूकार की दया पर निर्भर हैं। लगभग ६० वर्ष पूर्व भारत में सहकारी आन्दोलन के प्रारम्भ के साथ किसान को उसकी वित्तीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सह-साहूकार और जमींदारों के पजों से मुक्त करवाने का एक प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास किस हद तक सफल हुआ वह इस बात से स्पष्ट हो गया जब कि ग्रामीण उधार सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में यह बताया गया कि सहकारी आन्दोलन किसानों की कुल वित्तीय आवश्यकताओं के तीन प्रति शत हिस्से से अधिक की पूर्ति नहीं कर सका है। कुछ समय से सहकारी अभिकरण तथा सरकार दोनों ही ग्रामीणों की वित्तीय आवश्यकताएँ अधिकाधिक रूप से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक परिवर्तन की दृष्टि से इन बातों का बहुत महत्व है (१) किसी एक निश्चित अवधि के दौरान ग्रामीणों पर कर्जदारों, (२) विभिन्न वर्गों में कर्जदारी, और (३) परम्परागत, सरकारी और सहकारी अभिकरणों द्वारा प्रदत्त रकम का अनुपात।

प्रस्तुत लेख में मैसूर राज्य में बेल्लारी जिले के दो गाँवों के निवासियों की कर्जदारी का परीक्षण किया गया है। गाँवों के नाम हैं, चित्रपल्ली और हगरी बोम्मन्न

हल्ली (ह बो हल्ली)। पूना स्थित 'गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स' के तत्वावधान में इन गाँवों का १९५७-५८ में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के वक्त ह बो हल्ली में १,०१८ और चित्रपल्ली में २८८ घर थे। उक्त दोनों गाँव पास-पास हैं, लेकिन ह बो हल्ली चित्रपल्ली की तुलना में अधिक शहरीकृत है। प्रथम में लगभग ४० प्रति शत घर ही खेती पर निर्भर करते थे, जबकि द्वितीय में करीब ९० प्रति शत परिवार कृषि में लगे थे।

कर्जदारी की आम हालत

सर्वेक्षण के समय ह बो हल्ली पर कुल ४,४२,८३० रुपये और चित्रपल्ली पर ८५,०६० रुपये कर्ज था। ह बो हल्ली में प्रति व्यक्ति कर्ज चित्रपल्ली के प्रति व्यक्ति ६८ रुपये कर्ज की तुलना में ९० रुपये था। इसके विपरीत ऐसी भी जानकारी मिली है कि गाँव के कई लोगो ने स्वयम् गाँव अथवा बाहर रुपये ऋण स्वरूप दिये हैं। इस प्रकार ऋणस्वरूप दिया गया धन ह बो हल्ली में २,१०,०३० रु और चित्रपल्ली में १२,३७० रुपये था। गाँव की कर्जदारी की तुलना में ह बो हल्ली में यह ४३ प्रति शत और चित्रपल्ली में करीब १० प्रति शत था। यह मानते हुए कि उक्त समूची रकम गाँव के अन्दर ही दी गयी तो भी ह बो हल्ली में २,३२,८०० रुपये और चित्रपल्ली में ६२,६९० रुपये की कमी रहती है। ये कमियाँ अन्य गाँवों के स्वतंत्र व्यक्तियों अथवा उधार देनेवाले अभिकरणों द्वारा अवश्य ही पूरी की गयी होगी। बताया गया कि ह बो हल्ली में ७४,३९० रुपये

* लेख में व्यक्त विचार स्वयम् लेखक के हैं और योजना आयोग का प्राग्रैम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन—कार्यक्रम मूल्यांकन समूह—उनके लिए उत्तरदायी नहीं है।

सर्वेक्षण वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में उधार लिये गये। चित्रपल्ली में उक्त वर्ष में ६,८०० रुपये लिये गये। इसी काल में ह बो हल्ली ने ८८,७४० रुपये और चित्रपल्ली ने २२,६५० रुपये वापस लौटाये। उक्त वर्ष में कुल कर्ज की तुलना में ह बो हल्ली और चित्रपल्ली में क्रमशः २० और २७ प्रति शत कर्ज लिया गया तथा १७ और ८ प्रति शत वापस लौटाया गया।

ह बो हल्ली में ६३४ परिवार और चित्रपल्ली में १४९ घर कर्जदार थे। यद्यपि अधिकांश परिवारों ने एक-एक बार ही उधार लिया, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने तीन-तीन बार उधार लिया। ह बो हल्ली में एक-एक उधार लेनेवालों का प्रातिशत्य ७३ और चित्रपल्ली में २१ था। दो-दो बार उधार लेनेवाले परिवार १५ प्रति शत थे। चित्रपल्ली में तीन-तीन बार उधार लेनेवाले परिवार कुल कर्जदार परिवारों के तीन प्रति शत थे, लेकिन ह बो हल्ली में वे इसके तीन गुने प्रातिशत्य में थे। ह बो हल्ली के कर्जदार ६३४ परिवारों ने ८६४ ऋण अथवा उधार लिये। चित्रपल्ली के १४९ कर्जदार परिवारों ने कुल १८४ ऋण लिये। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षण वर्ष में ६२ २ प्रति शत परिवार ह बो हल्ली में और ५१ ७ प्रति शत घर चित्रपल्ली में कर्जदार थे।

उधार देनेवाले अभिकरण

इन गाँवों में उधार देनेवाले अभिकरणों (एजेसियों) को आठ वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। विभिन्न अभिकरणों ने जो ऋण दिया उसका विवरण तालिका १ में दिया गया है। यदि हम समग्र चित्र पर विचार करें तो देखेंगे कि ह बो हल्ली में सरकार ने तकावी के जरिये कुल उधार का ४४ प्रति शत और सहकारी समितियों ने ३४ प्रति शत प्रदान किया है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण उधार सर्वेक्षण के बाद तत्सम्बन्धी स्थिति में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि चित्रपल्ली में उक्त दोनों अभिकरणों का

योगदान प्रायः नगण्य है, जैसा कि तालिका १ से समझा जा सकता है। चित्रपल्ली की तुलना में ह बो हल्ली में

तालिका १

अभिकरणों के अनुसार बकाया ऋण का विवरण
(प्रातिशत्य)

अभिकरण	ह बो हल्ली		चित्रपल्ली	
	कुल उधार	कुल ऋण	कुल उधार	कुल ऋण
सरकार	४४	२७	०५	०६
सहकारी समिति	३४	३८	—	—
साहूकार	१७६	२९४	३३	७०
व्यापारी	२८०	२५१	३९७	३१२
भू-स्वामि	१६८	१७३	४०२	५२०
सम्बन्धी	९६	१०८	२७	१९
अन्य अभिकरण	१४२	७२	२२	१०
बिना व्याज का उधार	६०	३७	११४	६३
योग	१०००	१०००	१०००	१०००
वास्तविक	८६४	४,४२,८३०	१८४	८५,०६०

महाजनो का महत्व बहुत अधिक है, जैसा कि तालिका १ से प्रकट होता है, कि उन्होंने प्रथम गाँव में कुल का ३ प्रति शत और द्वितीय में कुल का १८ प्रति शत उधार उपलब्ध करवाया। ऐसा लगता है कि व्यापारियों ने विस्तृत पैमाने पर उधार देने का धधा अपना लिया है। दोनों ही गाँवों में उन्होंने सर्वाधिक उधार रुपया दिया। इनका प्रातिशत्य ह बो हल्ली और चित्रपल्ली में क्रमशः २८ तथा ४० था। भू-स्वामियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है—खास कर चित्रपल्ली में, जहाँ उन्होंने ४० प्रति शत उधार दिया। साथी-सगियों और रिश्तेदारों से बिना व्याज के लिया गया उधार ह बो हल्ली में ६ प्रति शत और चित्रपल्ली में ११ प्रति शत था।

सरकार, सहकारी समिति और महाजनो के मामले में द्वितीय उधार का अनुपात प्रथम से कम था तथा तृतीय उधार, उन्होंने, बिल्कुल दिया ही नहीं। व्यापारियों

के मामले में, जहाँ तक हूँ बो हल्ली का सवाल है, द्वितीय उधार का अनुपात प्रथम से ज्यादा था, यद्यपि तृतीय का अनुपात प्रथम दो से कम था। भू-स्वामियों, सम्बन्धियों तथा अन्य व्यक्तियों की पद्धति सरकार, महकारी समिति और महाजनो की पद्धति से ठीक विपरीत थी। इनके मामले में तृतीय उधार का अनुपात प्रथम दो उधारों से अधिक था। सम्भवतः जब सरकारी तथा अर्ध-सरकारी अभिकरण एक या दो से अधिक उधार देने में असफल रहे तब स्वतंत्र व्यक्तियों जैसे स्रोतों से सम्पर्क किया गया। हूँ बो हल्ली में तृतीय उधार का करीब ८६ प्रतिशत भूस्वामियों, सम्बन्धियों और अन्य साथी-सगियों से प्राप्त किया गया। चित्रपल्ली में तृतीय उधार का ४० प्रतिशत कृषकों ने दिया और शेष निर्व्याज रूप में दोस्तों, साथियों अथवा सम्बन्धियों ने दिया।

तालिका १ में विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिये गये उधार की सख्या तथा ब्याज सहित बकाया रकम भी दिखायी गयी है। उधार देनेवाले अनेक अभिकरणों

की बकाया रकम के अनुपात और दिये गये उधार की सख्या के अनुसार प्राप्त अनुपात में थोड़ा अन्तर मिलता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने कुल का ४४ प्रतिशत उधार दिया, लेकिन यदि हम कुल रकम को ले तो पता चलेगा कि हूँ बो हल्ली में यह प्रातिशत्य २७ है, हूँ। चित्रपल्ली में इसका अन्तर अवश्य नगण्य है। इसी प्रकार महाजनो द्वारा दी गयी रकम की दृष्टि से हम विचार करें तो पता चलेगा कि दोनों ही गाँवों में उनका स्थान काफी महत्वपूर्ण है—उधार की सख्या की दृष्टि से उनका प्रातिशत्य हूँ बो हल्ली और चित्रपल्ली में क्रमशः १८ और ३ है, लेकिन अगर कुल रकम की दृष्टि से हम देखें तो यह प्रातिशत्य क्रमशः २९ और ७ प्रतिशत है।

आय के अनुसार कर्जदारी

उक्त गाँवों के कर्जदार परिवारों को नौ आय वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसाकि तालिका २ में दिखाया गया है। यद्यपि कोई भी यह अपेक्षा कर

तालिका २

आय के अनुसार कर्जदारी

आय वर्ग	हगरी बोम्मन हल्ली			चित्रपल्ली		
	कुल परिवार	कर्जदार परिवार	कुल में कर्जदारों का प्रातिशत्य	कुल परिवार	कर्जदार परिवार	कुल में कर्जदारों का प्रातिशत्य
१०० रु तक	३	—	—	१	—	—
२५० रु तक	५१	२९	५६ ९	१३	१	० ८
५०० रु तक	१८६	१०२	५४ ८	४७	२१	४४ ७
७५० रु तक	२२९	१४७	६४ २	५८	४१	७० ७
१,००० रु तक	२३८	१५९	६६ ८	५०	२६	५२ ०
१,५०० रु तक	१५८	१०९	६९ ०	८०	३६	४५ ०
२,५०० रु तक	८४	५४	६४ ३	३२	१८	५६ ३
३,५०० रु तक	२१	११	५२ ४	६	५	८३ ३
३,५०० से ऊपर	४८	२३	४७ ९	१	१	१०० ०
योग	१,०१८	६३४	६२ ३	२८८	१४९	५१ ७

सकता है कि गरीबों में कर्जदारी का अनुपात अधिक होगा लेकिन तालिका २ में प्रस्तुत आंकड़ों से इस निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद नहीं मिलती। हमें बो हल्ली के मामले में हम देख सकते हैं कि प्रारम्भ से लेकर परिवार की आय बढ़ने के साथ ही कर्जदारी का अनुपात भी बढ़ता है, और केवल १,५०० रुपये के आय-स्तर पर पहुँचने के बाद ही कर्जदारी का अनुपात कम होने लगता है। तथापि, चित्रपल्ली के मामले में यह एक अजीब बात है कि आय बढ़ने के साथ ही मात्र कर्जदारी का अनुपात भी बढ़ता जाता है।

कर्जदार परिवारों में हमें बो हल्ली में न्यूनतम अनुपात (४८ प्रति शत) उन परिवारों का है, जिनकी वार्षिक आय ३,५०० रुपये से ज्यादा है। लेकिन चित्रपल्ली में १०१-२५० रुपये तक के आय वर्ग के १३ परिवारों में से केवल एक ही कर्जदार है। इस कर्ज को छोड़ कर बाकी के वर्गों में केवल दो मामले—वे परिवार जो २५१-५०० और १,५०१-२,५०० रुपये वाले आय वर्गों में आते हैं—ही ऐसे हैं, जिनमें कर्जदारी का न्यूनतम प्रातिशत्य (करीब ४५) है। हमें बो हल्ली में कर्जदारी का अधिकतम अनुपात (६९ प्रति शत) उन परिवारों में है, जो

१,००१-१,५०० रुपये के औसत वार्षिक आय-वर्ग में आते हैं। चित्रपल्ली में ऐसा लगता है कि सबसे धनवान सबसे खराब हालत में हैं। औसतन ३,५०० रुपये वार्षिक आयवाले सात परिवारों में से छ पर कर्जा बताया गया है।

उधार का कारण

उधार लेने के मौसम के बारे में दोनों गाँवों में यद्यपि कोई समानता नहीं है तथापि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनवरी से लेकर जून के अन्त तक का समय उधार लेने की दृष्टि से व्यस्त मौसम है, क्योंकि ८१ ९ प्रति शत उधार हमें बो हल्ली में और ८७ ६ प्रति शत चित्रपल्ली में इसी अवधि के दौरान लिया गया। यदि हम इस तथ्य पर विचार करें कि जून तक खेती का काम शुरू हो जाता है तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि खेती के लिए जो कुछ रकम आवश्यक हो वह जून से पहले ले ली जानी चाहिये। यही समय विवाह-शादी का भी रहता है। तालिका ३ से इसकी पर्याप्त पुष्टि हो जाती है। उक्त तालिका में कर्ज लेने के कारणों का विवरण दिया गया है। इस तालिका में हम देखते हैं, उधार के बहुत बड़े हिस्से की मवेशों और बीज

तालिका ३

उधार लेने के कारण

कारण	हमें बो हल्ली				चित्रपल्ली			
	उधार संख्या	प्रातिशत्य	रकम रु	प्रातिशत्य	उधार संख्या	प्रातिशत्य	रकम रु	प्रातिशत्य
अज्ञात	३	१ ३	१,५००	२ ०	—	—	—	—
भूमि खरीद	४	१ ७	२,६००	३ ५	१	३ १	३००	४ ४
पशु खरीद	२५	१० ८	९,५५०	१२ ८	९	२८ १	१,६१०	२३ ७
भूमि सुधार	२०	८ ७	५,११०	६ ९	१	३ १	१५०	२ २
मकान खरीद, मरम्मत आदि	१२	५ २	५,१२०	६ ९	१	३ १	४००	५ ९
गैर खेतिहर धन	२१	९ १	९,२००	१२ ४	२	६ ३	२८०	४ १
मौजूदा कृषिक आवश्यकताएँ	६३	२७ २	१०,५००	१४ १	९	२८ १	१,०३०	१५ २
शिक्षा	२	० ९	१,१००	१ ५	—	—	—	—
विवाह व अन्य उत्सव	२३	१० ०	७,८८०	१० ६	८	२५ १	२,९३०	४३ १
दवा-दारू	१०	४ ३	१,५६०	२ १	—	—	—	—
अन्य घरेलू जरूरतें	४६	१९ ९	१९,५००	२६ २	१	३ १	१००	१ ५
पहले के कर्ज की वापसी	२	० ९	७५०	१ ०	—	—	—	—
योग	२३१	१०० ०	७४,३९०	१०० ०	३२	१०० ०	६,८००	१०० ०

तथा खाद जैसी खेती सम्बन्धी अन्य चीजें खरीदने के लिए जरूर पड़ती हैं। इन कारणों के लिए सर्वाधिक अनुपात (२७ प्रति शत) में उधार लिया गया। घरेलू आवश्यकताओं का स्थान दूसरा है। ह बो हल्ली में तत्सम्बन्धी प्रातिशत्य २० है। अन्य कारणों में ह बो हल्ली में २५ प्रति शत और चित्रपल्ली में १० प्रति शत उधार विवाह तथा अन्य धार्मिक उत्सवों सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया गया।

उधार के लिए जमानत

दोनों गाँवों में उधार के लिए जमानत के रूप में अनेक प्रकार की सम्पत्ति पेश की गयी। इस प्रकार के मर्दों की सूची तालिका ४ में दी गयी है। तालिका

तालिका ४

उधार के लिए जमानत

(उधार का प्रातिशत्य)

जमानत का प्रकार	ह बो हल्ली	चित्रपल्ली
भूमि	२२ ८	२२ २
मकान	१३ ६	११ १
पशु	४ ५	कुछ नहीं
आभूषण	२७ ३	३३ ४
उपकरण	४ ५	कुछ नहीं
फसलादि	९ १	११ १
रुक्के	९ १	११ १
बिवरण अप्राप्य	९ १	११ १
	१००=२३१	१००=३२

से देखा जा सकता है कि जमानत के रूप में सर्वाधिक प्रचलित सम्पत्ति आभूषण है। उदाहरणार्थ २७ ३ प्रति शत उधार ह बो हल्ली में और ३३ ३ प्रति शत उधार चित्रपल्ली में आभूषण गिरवी रख कर प्राप्त किया गया। तालिका ४ से ही यह भी प्रकट होता है कि भूमि और मकान को बन्धक रखना उधार प्राप्ति का

एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग था। दोनों गाँवों में करीब २२ प्रति शत उधार भूमि बन्धक रख कर, और ह बो हल्ली में १४ तथा चित्रपल्ली में ११ प्रति शत उधार मकान बंधक रख कर प्राप्त किये गये। रुक्के, खड़ी फसल आदि पर भी उधार पैसा लिया गया और केवल ह बो हल्ली में ही कुछ उधार (नौ प्रति शत) पशु वन तथा छपकरणाँ पर प्राप्त किया गया।

गाँवों में उधार साधारणतया लघु कालीन अवधि पर दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि महाजन अपनी उधारी यथा सम्भव जल्दी उगाहने को तरजीह देते हैं, यद्यपि फिर से उधार देने में उन्हें कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि उधार यदि दीर्घ-कालीन आधार पर दिया जाता है तो वापसी आगे खींची जाती रहती है और कुछ उधार डूब जाता है। इसलिए जब तक पुरानी उधारी वापिस नहीं की जाती, महाजन नया उधार देने के प्रति अन्यमनस्क होते हैं। लेकिन देनदार भी इस सम्बन्ध में बड़ी अच्छी व्यवस्था कर लेते हैं, फसल काट कर वे पुरानी उधारी चुका देते हैं और फसल बोआई के समय अथवा अन्य किसी सकट के वक्त नये सिरे से उधार ले लेते हैं। ह बो हल्ली में करीब ५३ प्रति शत और पडोसी गाँव में ७५ प्रति शत उधार एक वर्ष से कम समय के लिए लिया गया। ह बो हल्ली और चित्रपल्ली दोनों ही गाँवों में करीब ८४ प्रति शत उधार तीन वर्ष से कम अवधि के लिए लिया गया। करीब तीन प्रति शत उधार ह बो हल्ली में अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिए लिया गया, लेकिन चित्रपल्ली में इतने लम्बे काल के लिए कोई उधार नहीं लिया गया।

अधिक उधार के लिए माँग

यह एक अजीब बात है कि अत्यधिक कर्जदारी (६२ २ प्रति शत परिवार कर्जदार थे) के बावजूद ह बो हल्ली में सर्वेक्षण से पहलेवाले वर्ष में ३३ परिवार, बताया गया कि, उधार नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन चित्रपल्ली के मामले में ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया। जिन कारणों के लिए उधार लिया गया उनके विश्लेषण

से पता चलता है कि १८ २ प्रति शत को भूमि खरीद अथवा भूमि सुधार के लिए ऋण की आवश्यकता थी, जबकि २४ २ प्रति शत को पशु खरीदने और ३६ ४ प्रति शत को गैर-खेतिहर कामों के लिए उधार की जरूरत थी। तथापि, इन परिवारों को जितनी रकम की आवश्यकता थी, वह छोटी-छोटी रकम थी, क्योंकि इन असफल मामलों में ८८ प्रति शत व्यक्ति एक-एक हजार से कम रुपये उधार स्वरूप लेना चाहते थे।

उधार लेनेवालों ने जिन स्रोतों का उपयोग किया उससे पता चलता है कि महाजनो के बाद—जिनके पास ३३ ३ प्रति शत परिवारों ने कोशिश की—सरकार तथा सहकारी समितियों ने ऋण चाहनेवालों में सबसे ज्यादा

परिवारों के प्रार्थनापत्र खारिज किये। लेकिन यह जानना कठिन है कि किन कारणों को लेकर उन्होंने ऐसा किया। तथापि, इन ३३ परिवारों को जिन कारणों से उधार की प्राप्ति नहीं हो सकी, इसका वर्गीकरण करने की कोशिश की गयी। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया कि ऋण या उधार प्राप्त करने की सामर्थ्य की कमी इन लोगों के रास्ते की मुख्य बाधा थी और इस कारण २९ ४ प्रति शत को असफल होना पड़ा। उधार प्राप्ति के इच्छुक २४ १ प्रति शत व्यक्तियों ने देखा कि उधार देनेवालों के पास पर्याप्त रकम नहीं थी।

शिमोगा (मैसूर) १६ अप्रैल १९६४

आबादी के विभिन्न वर्गों की असल आय में हुई सम्पूर्ण वृद्धि आय-वितरण पद्धति से सम्बन्धित आकड़ों और अनुमानों में प्रतिबिम्बित नहीं होती। असल आय, विशेषकर निम्न आय वर्ग वालों की, सरकार द्वारा प्रदत्त कई सेवा-सुविधाओं के कारण अधिकाधिक प्रभावित होती जाती है, जिसकी झलक आय सम्बन्धी आकड़ों में नहीं मिलती। कम-खर्च आवास, स्वास्थ्य, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और समाज कल्याण सेवा जैसी चन्द सेवाएँ निम्न आय वर्गों की अपेक्षितया असल आय अवस्था में सुधार लाती हैं और इस तरह असल आय के वितरण-संकेन्द्रण को कम करने की कोशिश करती हैं।

—रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड लेवलस ऑफ लिविंग, पार्ट १ (डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ एण्ड कंसेंट्रेशन ऑफ इकॉनॉमिक पावर)

जम्मू और कश्मीर में रेशम उत्पादन का विकास

माखन लाल भट

जम्मू और कश्मीर में रेशम उद्योग की अवस्था रेशम-कीट-पालन में वैज्ञानिक तरीके अपना कर-ताकि विदेशी रेशम-कीटों के आयात पर निर्भरता कम हो-सुधारी जा सकती है। यह लेख राज्य में रेशम उद्योग के विकास की ऐतिहासिक समीक्षा प्रस्तुत करने के साथ ही उन समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है, जिनका समाधान होने पर ही वह समृद्धि और अबाध विकास के दिन देख सकता है।

जम्मू और कश्मीर में आज किसानों का सबसे बड़ा सहायक घधा है रेशम-कीट-पालन। इसमें करीब ३,००० लोगों को पूर्ण-कालीन और ७०,००० परिवारों को अर्ध-कालीन काम मिलता है। लक्षावध तथा जम्मू प्रांत की दो तहसीलों को छोड़ कर राज्य के सभी भागों में रेशम-कीट पाले जाते हैं। इस उद्योग का आर्थिक महत्व, सम्पूर्ण देश के लिए भी, इस तथ्य से आका जा सकता है कि यह करीब ५० लाख लोगों को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और कुटीरो-द्योगी कर्मियों को आठ करोड़ रुपये से भी अधिक की शुद्ध आय कराता है।

कश्मीर की घाटी और जम्मू प्रान्त में प्रकृति का विपुल भण्डार है और शहतूत के वृक्षों की भी बहुतायत है, जोकि रेशम-कीटों का मुख्य भोजन है और उन्होंने रेशम उद्योग को इस राज्य की अर्थ-व्यवस्था में मुख्य स्थान दिलाया है। कभी शहतूत के वृक्ष घाटी में इतने घने उगते थे कि चन्द भागों को आज भी 'तुला-तार' कहा जाता है। कहा जाता है कि "शहतूत के वृक्ष इतने पास-पास उगते थे कि लोग वृक्ष-वृक्ष ही एक गोंब से दूसरे गोंब जा सकते थे, जमीन पर पैर रखने तक की जरूरत नहीं थी।"१

कश्मीर में रेशम उद्योग का कोई अधिकृत इतिहास नहीं है और नही इसके आरम्भ की कोई निश्चित उपलब्ध

तिथि बतायी जा सकती है, यद्यपि चन्द ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि राज्य में रेशम-कीट-पालन वैदिक काल में ही आरम्भ हो गया था। कुछ लोगों का कहना है कि रेशम उद्योग मध्य एशिया से यहाँ आया, जबकि वहाँ वह चीन से आया था। इतिहासकार मिर्जा हैदर (१५३६ ईसवी) ने रेशम उद्योग को बहुत ही उन्नत और आमदनी करानेवाला उद्योग बताया है।^२ कुछ अन्य रेकार्ड बताते हैं कि १८५७ तक कश्मीर बड़ी तादाद में रेशम-कीट-बीज पैदा करता था, जिसका अच्छा-खासा हिस्सा निर्यात किया जाता था। सबसे अधिक निर्यात १८५७ में हुआ, जबकि यूरोप को २५,००० औंस बीज निर्यात किये गये, क्योंकि 'पेन्नाडन' नामक घातक रेशम-कीट-बीमारी ने यूरोप के सारे रेशम कीटों को प्रायः समाप्त कर दिया था। भूत जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि "सन् १८६९ के पूर्व कश्मीर का रेशम उद्योग असंगठित और अपरिष्कृत अवस्था में था तथा सदियों से -उस समय से जबकि जीवाणु रेशम दमिश्क तथा अन्य निर्माण केन्द्रों को भेजा जाता था- वह वैसी ही अवस्था में रहता आ रहा था। इसमें सन्देह नहीं कि ईसा के पूर्व काल में कश्मीर जीवाणु राज्य का एक अंग था और पश्चिम को निर्यात किये जानेवाले कच्चे रेशम में से कुछ कश्मीर से भी आता था। कश्मीर में रेशम उद्योग का आरम्भ कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लोग इतना ही

जानते हैं कि बुखारा से इसका बड़ा गहरा सम्बन्ध है, जिससे कि यह हमेशा बीज और रेशम का लेन-देन करता रहा है।”^३

महत्वाकांक्षी

तत्कालीन शासक राजकुमार द्वारा विशेष दिलचस्पी लिये जाने के कारण १८६९ में वैज्ञानिक आधार पर पूरे रेशम उद्योग को सगठित और पुनर्जीवित करने का समोजित प्रयास किया गया, जिसके लिए बहुत अधिक खर्च कर आवश्यक यन्त्रों और उपकरणों का आयात भी किया गया। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में १०७ उत्तम रेशम-कीट-पालन गृह बनवाये गये और रेशम व्यापार का विकास करने हेतु एक बड़ा विभाग खोला गया। उसी वर्ष दो रेशम कारखाने (फिलेचर) भी खोले गये। इन दोनों ने ४७० रील तैयार किये, जिनमें से ४२ पानी से और बाकी हाथ से तैयार किये गये। कुल ९६४ कारीगर काम में लगे थे। सन् १८७३ में तैयार किया जानेवाला रेशमी धागा उत्तम किस्म का था, जोकि २४ शिलिंग प्रति पौण्ड के भाव पर बिकता था। उस वर्ष रेशमी सूत का २ लाख रुपये का व्यापार हुआ, जिसमें से करीब आधा मुनाफा था। यह प्रगति क्षणिक ही रही, क्योंकि पुनर्जीवन प्रदान करने की पद्धति सही नहीं थी। ‘किरम-कश’ (अर्थात् कीट मारनेवाले) नामक रेशम-कीट-पालकों का एक सघ बनाया गया और उन्हें बेगार जैसी प्रथा से छूट दी गयी।^४ उन्हें रेशम-कीट-पालन के लिए ग्रामीणों के घरों को अपना उपगृह बनाने की भी अनुमति दी गयी तथा उन्हें शहतूत के वृक्षों को पहुँचे नुकसान का समाचार देनेवाला भी नियुक्त किया गया। संक्षेप में “किरम-कश नाम से ही गाँववालों को घृणा हो गयी और

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रेशम-कीट-पालकों ने भी अपने दर्जे का नाजायज फायदा उठाया तथा लोगों को सताया। सारा काम बिल्कुल सरकारी हो गया और आम जनता इस उद्योग को हेय दृष्टि से देखने लगी।”^५ फिर, पुनर्जीवन प्रदान करनेवाला कार्यक्रम बहुत ही यह-वाकांक्षी था। भवन और सयत्र की लागत बहुत ही अधिक थी और रेशम-कीट-पालन गृह इस तरह बिखरे हुए थे कि उनके काम का उचित ढंग से पर्यवेक्षण नहीं हो पाता था। दुर्भाग्य से किसी को पर्यवेक्षण के लिए तकनीकल ज्ञान भी नहीं था और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था “जोकि १८७८ में इस उद्योग पर हुए प्रहार से—जबकि सारे कीट बीमारियों के शिकार हो गये—उसे बचा सकता।”^६ वे बीमारियाँ यूरोप, चीन और जापान से आयातीत बीजों के साथ आयी। यद्यपि वे बीज उत्तम किस्म के थे, परन्तु सिर्फ अपनी ही जलवायु में रहने के आदी थे।

सन् १८८२ से १८८९ तक यह उद्योग पूर्णतः रेशम-कीट-पालकों के हाथों में रहा। बीज की नस्ल तेजी से गिरती गयी और रेशम उद्योग प्रायः ठप-सा पड़ गया। कुल १२७ रेशम-कीट-पालन गृहों में से सिर्फ दो बच गये। सन् १८९० में भारत सरकार के तत्कालीन सचिव सर एडवर्ड बक के सुझाव पर इटली और फ्रांस से बीजों का आयात किया गया और फल-स्वरूप बहुत ही उत्तम कोये प्राप्त हुए। पर १८९१ में वही प्रगति नहीं बनी रही। फिर भी १९०३ में एक प्रसिद्ध अंग्रेज रेशम-विज्ञान शास्त्री के सुझाव के आधार पर ‘फिलेचर’ (रेशम उत्पादन कारखाना) खड़े करने शुरू किये गये और १९०६ तक छ ‘फिलेचर’ खड़े हो गये। सन् १९०७ में १० फिलेचर चल रहे थे, जिनमें ५,००० व्यक्ति काम करते थे इनमें भी मुख्यतः रेशम-कीट-पालक थे।

३. एम. जी. मुकर्जी, जिन्हें डब्ल्यू. एच. लॉरेन्स द्वारा वैली ऑफ कश्मीर में उद्धृत किया।

४. आलोच्यारि में, विशेषकर ग्रामीणों को स्थानीय राजा अथवा उसके एजेंट के लिए निर्माण कार्यों, माल परिवहन तथा अन्य कार्यों में से किसी में भी बेगारी का काम करने के लिए

कहा जाना था। काम के बदले में पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था। यह सरकार के विरोधियों को कुचलने के अनेक तरीकों में से एक था।

५. डब्ल्यू. एच. लॉरेन्स, वैली ऑफ कश्मीर।

६. उक्त उद्धृत।

अपने घरों में काम करनेवाले रेशम-कीट-पालकों को लगाकर इस उद्योग में ६०,००० लोग लगे थे। रद्दी से १,००,००० पौण्ड (करीब १४,००,००० रुपये) कीमत का कच्चा रेशम तैयार किया गया। तथापि, यह प्रगति १९१३ में श्रीनगर के कारखाने में भयंकर आग लग जाने के कारण कुछ समय के लिए रुक गयी, क्योंकि समूचा सयंत्र बेकार हो गया।

प्रथम विश्वयुद्ध

राज्य के मुख्य दो शहरों में बिजली लगी और उसी समय १९१४ में यूरोप में विश्वयुद्ध छिड़ गया, जिससे इस उद्योगों का सारा रूप ही बदल गया— कार्य संचालन के मामले में भी और सम्भावनाओं के विषय में भी। माँग अधिक होने से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमाने और तब तक हुआ बाटा पूरा करने का मौका मिला, बल्कि अधिकारियों को राज्य के अन्य हिस्सों में इसका कार्य-विस्तार करने की प्रेरणा भी मिली। फलस्वरूप १९१९ में १९०२ के मुकाबले ३४५ प्रति शत अधिक लाभ हुआ, जिसकी जानकारी नीचे दिये गये वार्षिक लाभ के आँकड़ों से मिलती है

वर्ष	औसत वार्षिक लाभ (लाख रुपयों में)
१९०२-१९०७	३ ६२
१९०७-१९१३	५ ९९
१९१३-१९१९	१२ ४९

चीनी प्रतियोगिता

युद्धोत्तर काल की अधिक माँग और फलत उच्च कीमत में शीघ्र ही इन कारणों से बाबा आ पहुँची रुपये का अस्थिर विनिमय मूल्य, चीनी प्रतियोगिता, विदेशी माँग में तथा उसमें भी विशेष कर अमेरिकी माँग में कमी जोकि सप्ताह में सबसे अधिक रेशम खपत करनेवाला देश था, और फिर सप्ताह भर में अवमूल्यन। इन आर्थिक परिवर्तनों ने उद्योग में मंदी ला दी। राज्य में तथा राज्य के बाहर माँग इतनी कम हो गयी कि रेशम

की कीमत प्रति पौंड ६४ प्रति शत तक कम करनी पड़ी। यही सब काफी मजबूती के साथ अपनाये रखना पड़ा, क्योंकि तब चीन और जापान अपने रेशम उत्पादनों को विश्व बाजार में प्रवेग कराने के लिए न सिर्फ अपने माल को घाटा उठा कर सस्ते में बेच रहे थे तथा यूरोपीय बाजार में एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि पूरब में जो ब्रिटिश उपनिवेश थे—जोकि हमारे रेशमी माल के मुख्य खरीदार थे— उनमें भी उन्होंने अपना माल भर दिया। विश्व में हुए इन परिवर्तनों का स्थानीय उद्योग पर इतना तीव्र प्रभाव पड़ा कि कच्चे रेशम का उत्पादन ५० प्रति शत से भी अधिक कम करना पड़ा। सरकारी रेशम उद्योगों में काम करनेवाले कारीगरों की संख्या और मजदूरी में बहुत कटौती करनी पड़ी। स्वभावतः ६० प्रति शत रेशम-कीट-पालक अपने कोये नहीं बेच सके।

दिनोदिन बढ़ती विदेशी प्रतियोगिता से इस उद्योग के हित की रक्षा के लिए सरकार से संरक्षण की माँग की गयी, जिसने उस आग्रह को ठुकरा दिया। विदेशी रेशमी माल पर आयात-शुल्क थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया, परन्तु यह कदम प्रभावी नहीं हुआ। चीनी-जापानी प्रतियोगिता घटने के बजाय बढ़ती गयी और इस प्रक्रिया में उन्होंने तरह-तरह के माल सस्ती कीमत पर दिये, जिससे स्थानीय रेशम उद्योग मिटने-मिटने जैसे हो गये। स्थिति और बिगड़े, इसके पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया।

बड़ी राहत

चीन और जापान के बिगड़ते सम्बन्ध एबम् बाब में जापान द्वारा शत्रु राष्ट्रों (एक्सिस पावर्स) के साथ मिल कर युद्ध की घोषणा करने तथा पैराशूट के लिए रेशमी कपड़ों की खरीद के लिए भारी तादाद में आर्डर प्राप्त होने से रेशम की माँग और कीमत दोनों ही काफी बढ़ी। चूँकि राज्य पूरी माँग की पूर्ति नहीं कर सका, इसने नागरिक कार्यों के लिए सिर्फ १५ प्रति शत उत्पादन के वितरण की अनुमति दी और शेष को युद्ध-माँग की

पूर्ति के लिए रख दिया। राज्य के अन्दर खपन के लिए कम उपलब्धि से काला बाजार करनेवालों को बहुत मुनाफा हुआ। जैसे १९२७ में एक पौण्ड रेशम की कीमत १२ १० रुपये थी, १९३४ में वह घट कर ३ ९ रुपये हो गयी, परन्तु १९४४-४५ में वह फिर से बढ़ कर १० ९५ रुपये हो गयी, जबकि काले बाजार में उसकी कीमत १५० रुपये तक पहुँच गयी।^७ रेशम उद्योग विभाग ने भी बड़ा मुनाफा कमाया तथा एक और रेशमी कारखाने की स्थापना की, जोकि काफी सफल रहा है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् होनेवाली निरन्तर प्रगति १९४७ में राज्य पर होनेवाले पाकिस्तानी हमले के कारण रुक गयी। अधिकांश रेशम-कीट-पालक विस्थापित हो गये, बिजली पूर्ति नष्ट कर दी गयी सरकारी विभाग के अभाव में शहतूत के बहुत-से वृक्ष काट डाले गये और सारी व्यवस्था ही बिगड़ गयी। राजनीतिक अस्थिरता, बिजली की कमी आदि के कारण १९५३-५४ तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। तथापि, वस्तुतः १९५३ के बाद, जबकि राज्य में नियोजित विकास कार्य का आरम्भ हुआ, राज्य के औद्योगिक स्वरूप में कुछ परिवर्तन करने की प्रोत्साहन मिला, जिसके फलस्वरूप अभी ७५३ रीलिंग बेसिन हैं, जिनमें इन फिलेचरो में एक पाली काम करते हुए एक साल में २ लाख ५० हजार पौण्ड रेशमी सूत कातने की क्षमता है।^८ सन् १९६२-६३ में कृषिक रेशम का उत्पादन १ लाख ५० हजार पौण्ड था। इस प्रकार सिर्फ ६० प्रति शत रीलिंग क्षमता का ही इस्तेमाल होता है। स्थापित क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल न होने के कारण ये बताये जाते हैं कोयो की अपर्याप्त पूर्ति, प्राचीन किस्म के यंत्र, अदक्ष कारीगर आदि। उपर्युक्त कथन कहाँ तक ठीक है, इसकी जाँच करने के लिए हम उद्योग के कुछ पहलुओं पर विचार करें। महत्वपूर्ण पहलू है

(अ) शहतूत के वृक्षों की खेती, (आ) बीज पुनरुत्पादन, (इ) रेशम-कीट-पालन तथा कोया उत्पादन, और (ई) फिलेचरो पर रेशमी धागे की रीलिंग अर्थात् लपेटाई।

२

शहतूत के वृक्षों की खेती

यहाँ का रेशम उद्योग शहतूती किस्म का है। शहतूत के वृक्षों की खेती पर सरकार का एकाधिकार है, जोकि पौधघरो की देखभाल करती है। इन पौधघरो में उगायी गयी शहतूती कलमें रेशम-कीट-पालको तथा जमींदारों के खेतों एवम् सरकारी भूमि और गाँव की सामूहिक भूमि में रोपी जाती है। ये कलम रेशमी-कीट-पालको को दी जाती हैं, जिनका अधिकार पत्तो पर होता है, वृक्ष और उसकी शाखाओं पर नहीं। यह बात सम्बत् २००६ (सन् १९४७) के शहतूत अधिनियम में बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके अनुसार शहतूत का वृक्ष “आरक्षित वृक्ष” है और कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी अनुमति के उसे काट नहीं सकता—वह व्यक्ति भी नहीं जिसकी भूमि पर वह वृक्ष हो। इसके अतिरिक्त शहतूत के पत्तों को सिर्फ रेशम-कीट-पालन के लिए ही इस्तेमाल करना है तथा रेशम-कीट-पालक का अपने तथा आस-पास के गाँवों अथवा सरकारी और निजी भूमि पर उगे हुए शहतूती वृक्ष पर अधिकार है, जिसका उपयोग वह निशुल्क कर सकता है।

रेशम-कीटों को खिलाने के लिए सफेद पत्ते सबसे उपयुक्त होते हैं। इस तरह की चन्द चीनी शहतूती कलमें १८७३ में मगायी गयी थी, और उनका यहाँ अच्छा विकास हुआ। इस तरह के उगाये और रोपे गये वृक्षों की संख्या १९२१ में २०,००० से कुछ ही अधिक थी, १९२४ में ४१,००० से ऊपर, १९३५ में ७०,००० से ऊपर, और १९४० में ८४,००० से ऊपर। वर्ष १९४३-४४ में युद्ध में बढ़ी माँग के कारण

७ एस एन कौल, कश्मीर इकनॉमिक्स, १९५६।

८ वर्तमान फिलेचरो की क्षमता, वर्ष में प्रति दिन आठ घण्टे

काम कर ३०० दिनों में प्राप्त रेशम के १८ प्रति शत दर के आधार पर तैयार की गयी है।

डेढ़ लाख रुपये के खर्च से साढ़े चार लाख शहतूत की कलमे लगायी गयी। अभी राज्य में इस तरह के कम से कम २० लाख शहतूत के वृक्ष हैं, जिनमें से अधिकांश लम्बे हैं और यह कहा जाता है कि अभी जितनी मात्रा में बीज वितरित किये गये हैं उसके लिए ये पर्याप्त नहीं हैं।^१ पत्तियों की सख्या में वृद्धि करने के लिए रेशम उद्योग विभाग ने ४६९ एकड़ क्षेत्र में फँले अपने ३२ पौधघरों से देशी और विदेशी दोनों ही किस्मों की कलमों को रेशम-कीट-पालकों में वृक्षारोपण के लिए निशुल्क वितरित किया है। बूढ़े हो गये तथा जनता द्वारा काट डाले गये वृक्षों की जगह नये वृक्ष लगाने में भी वह मदद करता है।

सन् १९५५ और १९५९ के बीच वितरित पौधों की सख्या तालिका १ में दी गयी है।

तालिका १

शहतूती पौध के रोपण में सफलता*

वर्ष	वितरित कलमों की सख्या (लाख में)	रोपी गयी कलमों की सख्या (लाख में)	बड़े वृक्षों की सख्या (लाख में)	बचे वृक्षों का प्रतिशत
१९५५-५६	१ ७८	१ ४२	० ९८	६९
१९५६-५७	१ ९७	१ २९	१ ०२	७९
१९५७-५८	१ ८९	१ ४९	० ८०	५४
१९५८-५९	अप्राप्य	० ५८	अप्राप्य	अप्राप्य

* अ. उद्योग और व्यापार विभाग, जम्मू और कश्मीर राज्य।
आ द्वितीय पंच वर्षीय योजना की सफलताएँ, जम्मू और कश्मीर राज्य।

इ वर्ष १९५८-५९ के बाद वितरित कलमों के आंकड़े राज्य द्वारा प्रकाशित नहीं किये गये हैं।

९. उद्योग और व्यापार मंत्रालय (भारत सरकार) जम्मू और कश्मीर राज्य के औद्योगिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन।

उद्योग के योग्य और सफल संचालन के लिए शुद्ध, रोग रहित बीजों की उपलब्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेरह वर्षों के लगातार विकास के बाद भी आज राज्य को आयात किये गये बीजों पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि रोग-रहित तथा वायुजलानुकूलित नस्ल प्राप्ति में असफलता मिली है तथा रेशम-कीटों में भारी मृत्योनुपात है। स्थानीय उत्पादन अन्दाज़न सिर्फ ३७,००० औंस है, जबकि छ सरकारी अन्न भण्डार हैं जोकि ६०,००० औंस बीजों का पालन कर सकते हैं। इसके पूरक रूप में जापान और फ्रांस से सामान्यतया ८,००० औंस बीज सालाना आयात किये जाते हैं। लगातार विदेशी पूर्ति पर निर्भर रहने से उद्योग को कई किस्म की जोखिम उठानी पड़ती है, जैसे बीमारी, असामयिक पूर्ति, विदेशी मुद्रा-विनिमय की कठिनाइयाँ, आदि।

तालिका २

आयातीत और राज्य में पुनरुत्पादित बीजों की मात्रा (लाख औंस में)

वर्ष	आयातीत	स्थानीय उत्पादित
१९५३-५४	० ०८	० ३३
१९५४-५५	० ०७	० ३६
१९५५-५६	० ०८	० ३८
१९५६-५७	० ०९	० ३४
१९५७-५८	० ०९	० ३७
१९५८-५९	० ०८	० ३६

स्रोत - जम्मू और कश्मीर राज्य रेशम उद्योग निर्देशालय।

अपने घरों में रेशम-कीट पालनेवालों को रेशमी-कीट-मुपत दिये जाते हैं। कश्मीर में रेशम-कीट पालन अप्रैल आर मई माह में होता है तथा जम्मू में मार्च व अप्रैल में। सरकार बीजों को कीटाणुरहित करने के

लिए दबाएँ तथा उसके इस्तेमाल का तरीका बतानेवाली स्थानीय भाषा में प्रकाशित पुस्तिकाएँ मुफ्त उपलब्ध करती हैं। ये पुस्तिकाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें जबानी याद किया जा सकता है। अभी कश्मीर में कोया-पालन से ५०,००० परिवारों को लाभ होता है और जम्मू में २०,००० परिवारों को। इस सहायक धंधे से रेशम-कीट-पालकों को सालाना १५ से २० लाख रुपये की अतिरिक्त आय हो जाती है, जो प्रति परिवार २२ से ३० रुपये पड़ती है। कभी-कभी रेशम उद्योग से होनेवाली आय रेशम उद्योग क्षेत्र के मूल्यांकित राजस्व से अधिक हो जाती है। इससे और अधिक आय हो सकती है, परन्तु रेशम-कीट-पालक उत्पादन, प्रशोधन, प्रहस्तन और बीज परिवहन में जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, वे बहुत पुराने हैं, जिससे अन्ततः उत्पादित रेशमी मूल की किस्म और मात्रा पर बुरा असर पड़ता है।

रेशम-कीट चटाइयों और कपड़ों पर पाले जाते हैं। स्टैण्ड और ट्रे सिस्टम तथा उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धतियों का अभी इस्तेमाल नहीं होता। वर्तमान प्रणाली हानिकारक है, क्योंकि इससे बीमारियाँ पैदा होती हैं, कीड़े मरते हैं जिससे पत्रों की भी बर्बादी होती है। धूप में सुखाये गये कोये हर तरह से असमान होते हैं। इसके अतिरिक्त पालकों के पास तापमान, आर्द्रता, वायु आदि अनुकूलित करने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है और न ही वे कीड़ों को खिलाने में पूरा ध्यान दे पाते हैं। शहदूत वे पत्ते और कीट के बीज मुफ्त मिलने से पालक इस धंधे में जितना ध्यान देना चाहिये, उतना नहीं देते। वे इसलिए भी अधिक रूचि नहीं लेते कि सरकार उनके सारे हरे कोये ६५ रुपये प्रति मन की निश्चित दर से खरीद लेती हैं।

व्यक्तिगत कोया-पालकों को प्रति व्यक्ति मुश्किल से एक औंस बीज सलाई किया जाता है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि वह एक निश्चित सीमा से ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता, भले ही वह कितना ही उत्साही क्यों न हो। एक औंस अण्डों से करीब ४०,००० कीट

पैदा होते हैं और ये १२० औंस रेशम पैदा करते हैं। राज्य में प्रति एक औंस अण्डों के पीछे औसत रेशम उत्पादन कम (सिर्फ ८० औंस) है, जबकि फ्रांस और इटली में वह १०८ औंस है। राज्य का औसत वार्षिक कच्चा रेशम उत्पादन २ लाख ३० हजार पौंड है। पिछले कुछ वर्षों का कोया-उत्पादन तालिका ३ में दिया गया है -

तालिका ३
कोया उत्पादन (लाख मन में)

वर्ष	कोया उत्पादन की मात्रा
१९५४	२५ १९
१९५५	२५ ५८
१९५६	२६ ८७
१९५७	२१ ९२
१९५८	१९ ७३

स्रोत : जम्मू और कश्मीर राज्य उद्योग और व्यापार मंत्रालय।

रेशम लपेटाई

राज्य में दोनों तरह की लपेटाई होती है—फिलेचर की तथा दूसरी तरह की भी—और कोयों की कीमत मैसूर तथा बगाल की तरह घटती-बढ़ती नहीं रहती। इससे उद्योग को बहुत बड़ा सहारा मिलता है, जिसे जल्दी अव्यवस्थित नहीं किया जा सकता। वर्तमान फिलेचर यंत्र पुराने हो गये हैं और लागत कम करने तथा स्तर ऊँचा करने के लिए उनकी जगह आधुनिक यंत्र लगाने की आवश्यकता है। स्थानीय कीट-पालकों से खरीदे गये कोये छाटने के बाद उबले पानी में रखे जाते हैं, ताकि उनका लसलसापन कम हो जाय। इन कोयों से लपेटे गये धागों का परीक्षण विशिष्टीकरण के अनुसार करते हैं और फिर दक्ष लोग उनकी सलाई करने के बाद तह सगा कर पैक कर देते हैं। किसी भी

प्रकार का रेशम बिना लचीलापन, तनाव क्षमता और सुन्दरता परीक्षण से गुजरे कारखाने के बाहर नहीं जा सकता। रेशम डेनीयर १३।१५ से ३२।३६ तक के होते हैं। तैयार रेशम को उपयुक्त श्रेणियों में विभाजित करते हैं जैसे लोटस, टुलिप, आयरिस, सैफॉन, नील ए, नील बी आदि। एक दिन में सभी फिलेचरो से अधिकतम १,५०० पौण्ड लपेटा रेशम प्राप्त होता है। सन् १९४१ में राज्य में रेशम का वार्षिक उत्पादन—रही रेशम को छोड़ कर—२ लाख ३२ हजार पौण्ड था। सन् १९३८ में भारत का कुल रेशम उत्पादन १५ लाख पौंड था अर्थात् उसमें कश्मीर का योगदान १५ प्रति शत था। सन् १९४७ के बाद उत्पादन काफी घट गया और पिछले कई वर्षों से उत्पादन में कोई खास घट-बढ़ नहीं हुई है, जैसाकि तालिका ४ से स्पष्ट है।

रेशम उत्पादन का वह ५५ प्रति शत थी, जबकि १९५८ में वह ९३ प्रति शत हो गयी। जापान में इसकी मात्रा ३५ प्रति शत ही है। यह बड़ा नुकसान है, जिसे आधुनिक और उपयुक्त यंत्र स्थापित कर दूर किया जा सकता है या फिर छीजन इस्तेमाल का यंत्र स्थापित कर। छीजन इस्तेमाल यंत्र अभी स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि केन्द्रीय रेशम मण्डल (सेण्ट्रल सिल्क बोर्ड) के विशेषज्ञों के अनुसार अभी जितनी छीजन होती है, उसके लिए यंत्र स्थापित करना आधिकार्य से लाभदायक न हो कर खर्चीला ही होगा।

समस्याएँ

उपर जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनसे कई समस्याएँ सामने आती हैं, उदाहरणार्थ

१ बीज उत्पादन में राज्य स्वावलम्बी नहीं है, जिसके फलस्वरूप बीज आयात करने पड़ते हैं। तैयार किये जानेवाले कोये विभिन्न नस्लों के होते हैं, जिससे

तालिका ४

कच्चे रेशम का उत्पादन, खपत और निर्यात

(लाख पौंड में)

वर्ष	उत्पादन			स्थानीय उपभोग		अन्य राज्यों को निर्यात	
	कच्चा रेशम	रेशम छीजन	३ का २ से प्रातिशत्य	कच्चा रेशम	रेशम छीजन	कच्चा रेशम	रेशम छीजन
१	२	३	४	५	६	७	८
१९५१	१ १९	—	—	—	—	—	—
१९५४	१ ६८	० ९३	५५	० ७९	—	० ६६	० ८०
१९५५	१ ६०	१ ०५	६६	१ ०६	—	० ४७	१ ०४
१९५६	१ ७७	१ २७	७२	० ९४	—	० ८५	१ १८
१९५७	१ ४४	१ १५	८०	१ २९	—	० ८७	० ९५
१९५८	१ ००	१ ९३	९३	० ६२	—	० ०५	० ०७
१९५९	१ ३८	—	—	—	—	—	—
१९६०	१ ८६	—	—	—	—	—	—
१९६१	१ २९	—	—	० ७१	—	० १४	—

स्रोत डाइजैस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, योजना विभाग, जन्म और कश्मीर राज्य।

तालिका ४ से यह प्रत्यक्ष है कि कुल उत्पादन में कमी होने के अभाव में रेशम छीजन की मात्रा भी बढ़ती ही जा रही है। सन् १९५४ में कुल कच्चे

रूपेदाई में कठिनाई होती है।

२ आयातीत रेशम-कीट रोग-रहित नहीं रहे हैं। वस्तुतः यूरोप हमें बीज देता रहा है, जिस कारण कोचो

के उत्पादन में कमी आयी है और कीट-पालन गृह कई बीमारियों के स्थायी घर हो गये हैं।

३ पत्ते (कीटों की खुराक) कम मात्रा में उपलब्ध है और फलतः कोयों का उत्पादन अपर्याप्त है, जिससे श्रीनगर और जम्मू में स्थापित यंत्र निरन्तर काम नहीं कर सकते।

४ रेशम-कीट-पालन पद्धति बहुत पुरानी है।

५ फिलेचरो की स्थापना ६० वर्ष पूर्व की गयी थी और इन पुराने यंत्रों के कारण छीजन ज्यादा होती है और उत्पादन कम।

६ विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और अनुसंधान की तुच्छ व्यवस्था।

सरकारी पहल

उपर्युक्त सभी बातें परस्पर सम्बन्धित हैं और एक में सुधार होने से दूसरी में भी होगा ही, जिससे अन्ततः उत्पादित रेशम के स्तर और परिमाण पर भी प्रभाव पड़ेगा। तथापि, इन समस्याओं का हल करने के लिए द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भिक वर्ष १९५६ से राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। द्वितीय योजना में ५६ लाख रुपये की बटित निधि में २३ लाख रुपये रेशम उद्योग के विकास पर खर्च हुए, जबकि तृतीय योजना में इसके लिए ७५ लाख रुपये की राशि रखी गयी है। इन ७५ लाख रुपये में से ४७ लाख रुपये पूँजीगत कार्यों में खर्च होंगे। यह निवेश उद्योग की भौतिक बाधाओं को दूर करने में किस हद तक सफल अथवा असफल रहा है, वह निम्न तथ्यों से स्पष्ट है

मद (१) के लिए अधिकारियों ने कुछ कार्यवाही की है और उन्हें स्थानीय अवस्थाओं के उपयुक्त पैतृक नस्ले उत्पन्न करने में भी कुछ सफलता मिली है। इस कार्य के लिए १५० एकड़ भूमि पर बुनियादी बीज केन्द्र शहतूत बाग बनाया गया है। आशा है कि १९६४ से यह विभाग इस अवस्था में आ जायेगा कि धीरे-धीरे

बीजों का आयात कम होता जायेगा। तृतीय योजना के अन्त और चतुर्थ योजना के आरम्भ तक कश्मीर न सिर्फ अपनी खपत के लिए अच्छे किसम के बीज पैदा करने लगेगा, बल्कि इस अवस्था में भी आ जायेगा कि देश के अन्य राज्यों को बीज निर्यात कर सके। यह योजना केन्द्रीय रेशम मण्डल (सेण्ट्रल सिल्क बोर्ड) द्वारा प्रवर्तित है और भारत के रेशम उत्पादक राज्यों में बुनियादी बीज उत्पादन कार्यक्रम का एक अंग है।

व्यक्तियों के हाथों में

उपर्युक्त योजना ने जो प्रगति की है, उसे देखते हुए यह लगता है कि लक्ष्य और अन्दाज पूरे नहीं हो पायेगे। स्थायी हल और बीजप्राप्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए “यह अच्छा होगा कि रेशम-कीट-बीज का उत्पादन विकेन्द्रित कर दिया जाय, सरकारी हाथों से निकाल कर व्यक्तियों के हाथों में दे दिया जाय, जिन्हें कि लाइसेंसशुदा होना ही चाहिये और आवश्यक योग्यताएँ व काम का अनुभव भी होना चाहिये। इसका लाभ यह होगा कि इस काम को अधिकाधिक लोग अपनायेंगे।”^{१०} श्री लॉरेस ने भी इस तरह का सुझाव दिया जबकि उन्होंने यह कहा कि “सरकार को सिर्फ स्वस्थ बीजों के उत्पादन का ही काम अपने हाथ में रखना चाहिये और रेशम-कीट-पालन तथा रेशम लपेटने का काम छोड़ देना चाहिये।”^{११} इस तरह की व्यवस्था जापान जैसे देशों में सफल रही है, जहाँ कि कई व्यापारिक संस्थाओं के अपने प्रयोग और अनुसंधान केन्द्र, अन्न भण्डार, रेशम-कीट-पालक ग्राहक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनमें से कई की अपनी रेशम-कीट-जातियाँ हैं।^{१२}

कोया उत्पादन के लिए चुनिन्दा क्षेत्र निर्धारित है, जहाँ कि अच्छे बीज, प्रति औंस उत्तम उत्पादन और

१०. ‘रिपोर्ट ऑफ दि लेबर सब-कमेटी ऑफ सेण्ट्रल सिल्क बोर्ड,’ १९५८।

११. डब्ल्यू एच लॉरेस वेली ऑफ कश्मीर।

१२. इकीम अली दिसिल्क इण्डस्ट्री ऑफ जापान, १९५४।

पालन के लिए अनुकूल अवस्थाएँ हैं। अच्छा उत्पादन करनेवाले क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में जोड़ दिया जाता है और कम उत्पादन करनेवालों को निकाल दिया जाता है। रेशम-कीट-पालन गृहों में वर्ष में एक बार विभाग द्वारा कीटाणुनाशक दवाइयों मुफ्त छिड़की जाती है। विभागीय देख-रेख में अभिजनन केन्द्रों में सामूहिक कीट-पालन किया जाता है। बुनियादी बीज-कोया केन्द्रों में मनोनीत जातियों के बीजों के उत्पादन और उनसे 'पी १' बीज के तथा फिर उससे औद्योगिक बीज-कोयो के उत्पादन की योजना से न सिर्फ सफल फसल सुनिश्चित किये जाने की, बल्कि उसी स्तर के शहतूत के पत्तों से अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने की भी आशा की जाती है।

रोगों को भटाने के लिए कीट-पालन कमरों में ४० प्रति शत फारमेलिन वाष्पीकरण का तरीका अपनाया गया है। यह तरीका कम खर्चीला तो है ही, साथ ही इसके और भी कई लाभ हैं। इसने बीमारियों से पैदा होनेवाले नुकसान को कम कर दिया है। वर्ष १९६०-६१ में कश्मीर में फारमेलिन छिड़का गया तो दो वर्ष पूर्व हुए १७ हजार मन कोया-उत्पादन के मुकाबले २७ हजार मन कोयो का उत्पादन हुआ। इस रोग के दूर हो जाने से उद्योग इस योग्य हो गया कि वह बड़ी मात्रा में कोये प्राप्त कर सका, जिससे चीनारनामक उत्तम किस्म के रेशम का उत्पादन हो सका, और जिसने भारत के जरी बाजार में अपना स्थान बना लिया है तथा धीरे-धीरे जापानी रेशम के स्थान पर उसका इस्तेमाल प्रचलित होता जा रहा है।

कीट-पालकों को प्रोत्साहन

कोया-पालकों को सरकार जो कीमत देती थी वह घटती-बढ़ती नहीं थी। उत्पादन उत्तम हो अथवा निम्न, एक ही कीमत दी जाती थी। सारा माल ६५ रुपये मन के भाव से खरीदा जाता था जिसका परिणाम यह होता था कि पालक स्तर का ध्यान रखते ही नहीं थे। हाल ही में मूल्य में परिवर्तन कर सरकार ने पालकों

को प्रोत्साहन दिया है। प्रथम पालन के लिए ५ रुपये मन और द्वितीय पालन के लिए १५ रुपये मन भाव बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पालकों में प्रतियोगिता लाने के लिए पुरस्कार देना भी जारी किया गया है। यह मामूली परिवर्तन है और इससे कुल उत्पादन में— मात्रा और स्तर दोनों ही मामलों में—कोई खास फर्क नहीं आयेगा।

राज्य सरकार ने बीमारियों को खत्म तथा बीजों की पूर्ति करने की ओर भी ध्यान दिया है। परन्तु अब तक इसने जिस बात को नजरअन्दाज किया है, वह यह है कि व्यक्तिगत पालकों को शहतूत-बीज की पूर्ति कुल शहतूती पत्तों की पूर्ति से जुड़ी हुई है। अभी शहतूत के वृक्ष सड़कों के किनारे, कब्रिस्तानों, नालों, टीलों, निजी खेतों और नहरों के किनारे उगाये जाते हैं। परन्तु ये वृक्ष अधिक उम्र और विकास योजनाओं, सड़क विस्तार, पुल-निर्माण तथा नयी नहरों की खुदाई के कारण तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शहतूत के वृक्ष 'आरक्षित वृक्ष' हैं और निजी खेतों को उम्दा कलमें रोपने के लिए प्रेरित करना कठिन है। जब-तक वे उप-ध्वजे के रूप में स्वयम् ही रेशम-कीट-पालन का कान नहीं करते तब तक उनके खेतों में उगे शहतूत के वृक्षों से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनके पत्तों को कीट-पालक मुफ्त ले जा सकते हैं।^{१३} अभी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकारी विभाग को इन पेड़ों की देख-रेख तथा पालकों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ी सख्या में क्षेत्रीय कर्मचारी रखने होते हैं। कीट-पालक सामान्यतया वृक्षों के मालिक नहीं होते। अतः तेजी से नष्ट होते जा रहे शहतूत के वृक्षों और पालकों में पहल की कमी की यह दोहरी समस्या बहुत हद तक हल की जा सकती है यदि जंगलों के किनारे शहतूत के बीजों से शहतूत की झाड़ियाँ उगाने

१३ रिपोर्ट ऑफ इण्डस्ट्रियल सर्वे ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट, विकास आयुक्त (एस एस. आर), भारत सरकार।

की योजना बनायी जाय। फिर, शहतूत की झाड़ी उगाने से टोकरियाँ बनानेवालों को सहायक-धधा भी मिल जायेगा और प्राप्त छाल से कागज तैयार दिया जा सकेगा।

चूँकि जम्मू और कश्मीर राज्य चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अंत तक अभी के मुकाबले इसी किस्म का पांच गुना अधिक रेशम उत्पादन करने की आशा रखता है, अतः प्रादेशिक रेशम अनुसंधान केन्द्र की स्थापना आवश्यक है। भारत में यही एकमात्र एक फसली (यूनिवोल्टाइन्) क्षेत्र है, जोकि औद्योगिक पैमाने पर कोयो का उत्पादन करता है। यह केन्द्र चन्नापटना केन्द्र के पैमाने पर ही सम्भवतः संगठित किया जा सकता है और कश्मीर घाटी में खोला जा सकता है।

यदि इस उद्योग को अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करना है तथा वर्तमान माग बनाये रखनी है, तो मूल्य

को ध्यान में रखना होगा, ताकि तैयार माल खरीदार की क्रय-शक्ति के अन्दर हो। अभी देशी रेशम की कीमत चीन और जापान में उत्पादित रेशम से बहुत ज्यादा है।^{१४} इसका मुख्य कारण उत्पादन की अधिक लागत है।

इस राज्य में इस उद्योग की बहुत अधिक सम्भाव्यताएँ हैं, क्योंकि उपयुक्त वातावरण, कच्चे माल की प्रचुर प्राप्ति और सस्ता श्रम आदि अनेक लाभ यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों से इस उद्योग को टैरिफ संरक्षण का लाभ मिलता रहा है। अतः यदि संयोजित प्रयास किया जाय तो यह उद्योग राज्य का सबसे बड़ा कार्य बन जायगा, जिसमें राज्य की तीन-चौथाई कृषि आबादी को सहायक धधा देने की क्षमता है।

वस्त्रम विधानगर (गुजरात): २१ मई १९६४

१४ टैरिफ कमीशन ने अपनी हाल की रिपोर्ट में यह व्यक्त किया है कि जब तक कच्चे रेशम की कीमत मौजूदा स्तर (घाटी में हाथ करवा बुनकरों को कच्चा रेशम औसतन ३४ रुपये ५० पैसे की दर से दिया जाती है) जितनी ऊँची रहती है, आगामी पाँच वर्षों में शुद्ध रेशमी सूत की घरेलू वार्षिक माग ४० लाख पौण्ड से बढ़नेवाली नहीं

है। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि जब तक मौजूदा दो इकाइयों की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता, जम्मू और कश्मीर राज्य में अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये। भारत सरकार से इसे स्वीकार कर लिया है।

ऊनी और पशम वस्त्रों में सुधार के लिए भेड़-पालन

पेकब श्रीरामलू पैंटो

अच्छे स्तर का ऊन उत्पादन भेड़ की नस्ल पर निर्भर करता है जो कि वातावरण पालन, जलवायु-परिस्थितियों, मिट्टी, भोजन आदि से प्रभावित होती है।

मनुष्य मँमेलिया वर्ग की कई जातियों के पशुओं की खाले प्रागैतिहासिक काल से इस्तेमाल करता चला आ रहा है। कई पशुओं से थोड़ा-थोड़ा ऊन प्राप्त होता है, परन्तु विश्व में ऊन का सर्वाधिक भाग पालतू भेड़ों से प्राप्त होता है। करीब करीब प्रत्येक सम्य देश में भेड़ और बकरी पालन का काम होता है। एक नस्ल की भेड़ से दूसरी नस्ल में जो अन्तर होता है, वह भिन्न वातावरण और आबहवा के कारण। वस्त्रोद्योग में बहुत तरह और गुण के कच्चे माल इस्तेमाल किये जाते हैं और उनसे किस्म-किस्म के विभिन्न गुणों और उपयोग वाले वस्त्र तैयार किये जाते हैं। भेड़ के अलावा अन्य पशुओं से प्राप्त ऊन और बाल का भी वस्त्रोद्योग में काफी इस्तेमाल होता है। ससार के वस्त्रोद्योग उत्पादन में ऊनी वस्त्र का तीसरा स्थान है और कुल वस्त्र-उत्पादन का करीब १७ प्रति शत।

स्पैनिश मेरिनो भेड़-पालन और उसके विकास ने भेड़ की नस्लों को उन्नत बनाया है तथा स्पेन के मेरिनो भेड़ के आगमन के बाद ऊनी-उद्योग में काफी सुधार हुआ है।

प्रारम्भिक विकास

यूरोपीय राजाओं तथा स्पेन के राजवंश के बीच का सम्बन्ध और उनके द्वारा प्रस्तुत इन पशुओं ने सारे ससार में धीरे-धीरे ऊन उद्योग का विकास किया है। एशिया की पहाड़ी और बाद में यूरोप की जगली भेड़ों की नस्ल है ये पालतू भेड़। ये भेड़ अर्गेलिस मौफलन्स हैं और इनके पहले की नस्लों का शरीर बड़े बड़े बालों से ढका होता

था जिनमें चमड़े से सटे ही छोटे-छोटे मुलायम बाल भी हुआ करते थे।

मनुष्य ने भेड़-पालन दूध, खाले और मांस प्राप्त करने के लिए आरम्भ किया। ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व फिनिशियनों ने ऊन काटने हेतु बढिया ऊनवाली भेड़ का पालन आरम्भ किया। इंग्लैंड में रोम का राज्य होने के पूर्व ही भेड़-पालन आरम्भ किया गया और रोमन लोगों ने वहाँ स्थित अपने सैनिकों की वर्दी-भूति के लिए एक ऊनी कारखाना स्थापित किया।

दो प्रकार की भेड़ें

तेरहवी सदी में ग्रेट ब्रिटेन ससार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश था। स्पेन में १४ वी और १७ वी शताब्दी के बीच भेड़ का विकास किया गया और १५ वी से १७ वी शताब्दी के बीच झुंड के झुंड भेड़े हो गयी जि हे दो श्रेणियों में बाटा गया (अ) एक स्थान में रहनेवाली भेड़े और (आ) जगह-जगह घूमनेवाली भेड़े। जगह-जगह घूमने-वाली भेड़े पिछले नवम्बर में पैदा हुए भेड़ों के साथ अप्रैल के मध्य में उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देती और एक चरागाह से दूसरे चरागाह को पार करती हुई ६ सप्ताह में २०० मील आगे बढ़ जाती और फिर वहाँ सितम्बर तक रह कर दक्षिण की ओर वापस लौटना शुरू कर देती। स्पेन में भेड़ पालन के कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी तथा भेड़ों का निर्यात कानूनन मना था। इसलिए ये नस्ले अन्य देशों में (अ) राजकीय उपहार द्वारा और (आ) पुर्तगाल के जरिये चोरी-छिपे भेजी जाती थी। स्पेन की उत्तम मेरिनो भेड़ों ने

दूसरे देशों की स्थानीय भेड़ों से मिलकर वहाँ की भेड़ों में बहुत सुधार किया। स्पेन के राजा ने सेक्सोनी के इलेक्टर को उपहार स्वरूप जो मेरिनो भेड़ दिये उनसे मेरिनो की सेक्सोनी इलेक्ट्रियल भेड़ पैदा हुई। इस प्रकार मूर लोगो द्वारा सर्व प्रथम पालित मेरिनो भेड़ों ने दो मुख्य जातियों को जन्म दिया (अ) छोटे छोटे पैरोवाली नेगरेटी जिसे कि बाद में इन्पैण्टडोज कहा गया। इन भेड़ों से, जिनके गले बहुत ही झालरदार थे, फ्रेंच रैम्बूडलेट आस्ट्रेलियन इम्पीरियल नस्ल प्राप्त हुई। (आ) लम्बे पैरोवाली इसक्यूरियल भेड़ें जो कि सेक्सोनी इलेक्टोरियल में विकसित की गयी। १८ वीं सदी के बाद वाले हिस्से में मेरिनो भेड़ के निर्यात के जरिये ससार भर में उन उद्योग की स्थापना हुई।

वातावरण का प्रभाव

ऊनी रेशों पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है तथा अनुभव और पर्यवेक्षणों ने यह सिद्ध किया है कि अनुकूल अवस्थाओं में ऊन की मुलायमियत, गुण और स्तर में बहुत सुधार किया जा सकता है। ऊन के मूल्य और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में कई महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जैसे रेशों के व्यास अथवा लम्बाई, कटे बालों में कितनी अशुद्धता है अथवा बाल कितने सिकुड़ते हैं, मजबूती, रंग, चमकीलापन तथा वानस्पतिक तत्व। ऊनी रेशों के ये सभी गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इनमें जिस झुण्ड से ऊन की प्राप्ति हुई है तथा नस्ल और भौगोलिक स्थान के अनुसार बहुत भिन्नता पायी जाती है। रेशों को सूत और फिर वस्त्र में बदलने से अतिरिक्त भौतिक गुण, जैसे आकार, सिकुड़न, मुनम्यता, लचीलापन, ठोसत्व, आर्द्रता, विद्युत् तत्व, गर्मी, बुनाई योग्यता, अपेक्षित गुरुत्व आदि, भी स्पष्ट हो जाते हैं।

वातावरण में ये चीजें शामिल हैं १ भौगोलिक विभाग २ तापमान, ३ बारिश, ४ भौगोलिक रचना (अ) रासायनिक स्वरूप क्रियात्मक प्रभाव, (आ)

भौतिक स्वभाव, हस्तन प्रभाव (इ) धारण क्षमता, बहाव और वनस्पति ५ चरागाह और ६ आकाश।

प्रवरणशील प्रजनन की दक्षता

ऊन और पशु के प्रकार नस्ल तथा वातावरण एवं पशुपालन की अवस्था पर निर्भर है। इन उद्देश्यों से व्यवस्थित ढंग से प्रवरणशील प्रजनन का मार्ग अपनाया जा सकता है सास इलाके या आबहुवा अथवा विशेष अवस्थाओं के लायक नस्ल पैदा करना, विशेष बातें लागू करना जैसे पैरो को सड़ने से बचाना, अच्छे पालन की भावना का विकास, जनन-क्षमता, बहु-प्रजनन, जुड़वा भेड़ की पैदाइश, झुण्ड में बंध कर रहना आदि, ऊन के तन्वों में सुधार अथवा सशोधन करना, मास, जोड़ों के आकार, महक, युवा होने के समय को प्रभावित करना तथा मास और ऊन व्यापार के लिए पशु पैदा करना। परिणाम प्रवरणशील प्रजनन की दक्षता और पालन की योग्यता तथा सावधानी पर निर्भर है और इन बातों के ज्ञान की कमी-बेसी के साथ ही परिणाम भी भिन्न होते हैं।

यद्यपि ऊन के विकास को आबहुवा, मिट्टी और भोजन प्रभावित करते हैं, तथापि ऊन के सफल विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है नस्ल, क्योंकि हर किस्म की भेड़ खासियत लिये होती है। भेड़ अपनी रक्षा और आराम के लिए ऊन पैदा करती है, जो कि जिस आबहुवा में उसका पालन-पोषण होता है उसके अनुसार भिन्न होता है। जब भेड़ों को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं, तब आबहुवा के कारण होनेवाले परिवर्तन नज़र आते हैं। यह पशु शीतोष्ण कटिबंध में २०° आकाश से ६०° आकाश तक जीवित रहते हैं। सर्वोत्तम भेड़-पालन करनेवाले देश ३०° आकाश पर हैं। सबसे उत्तरी देश आइसलैंड और सबसे दक्षिणी देश हैं फाकलैंड द्वीप-समूह और पैटागोनिया। भेड़ (प्रत्यक्षत शेवियट) उत्तर ध्रुव वृत्त में भी रहती है, परन्तु जाड़े के दिनों में जून्हे घरों में बन्द रखते हैं जिस तरह की ग्रेट ब्रिटेन में गायों को

रखा जाता है।

(१) उत्तरी गोलार्ध में वितरण (अ) पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, (आ) पूर्व में रूस, तुर्की, पश्चिम, अफगानिस्तान तिब्बत और चीन।

(२) दक्षिणी गोलार्ध में वितरण (अ) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, (आ) दक्षिण अफ्रीका, (इ) दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका में उरुगुवे।

आबहवा का प्रभाव

भेड़ और उसके ऊन के विकासार्थ सामान्य और सम-तापमान सर्वाधिक उपयुक्त है। तापमान का प्रभाव ऊन के उत्पादन पर दिखाई देता है। मेरिनो किस्म की भेड़ों से सर्वोत्तम ऊन प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान है 60° से 64° फॉरेनहाइट। उससे अधिक तापमान होने से ऊन बाल की तरह के होने के अलावा कड़े और सूखे होते हैं। उदाहरणार्थ पेरू, अरब, पश्चिम, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में औसत तापमान 70° फॉरेनहाइट रहता है और इन इलाकों में उत्पन्न ऊन बालनुमा, रखड़े, कड़े और सामान्यतया छोटे रेशेवाले हुआ करते हैं। आइसलैंड के उत्तरी प्रदेशों और उत्तरी स्कॉटलैंड में, जहाँ आबहवा ठंडी है, भेड़ की खाल की निचली सतह पर बहुत ही सुन्दर और गर्म ऊन की परत रहती है। जिन क्षेत्रों में दिन में भीषण गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहाँ की भेड़ों में छोटे रेशे के ऊन की निचली सतह के ऊपर अवरऊनमय केशी परत रहती है। जिन क्षेत्रों में तापमान 60° फॉरेनहाइट (ग्रेट ब्रिटेन में 40° — 60° फॉरेनहाइट) से कम रहता है, वहाँ की भेड़ों का ऊन मजबूत होता है पर उतना सुन्दर नहीं, उसके रेशे लम्बे होते हैं, उसका विकास नियमित और सही होता है। जिन क्षेत्रों में जाड़े और गर्मी के मौसमों में तापमान 30° फॉरेनहाइट से अधिक अन्तर रखता है, वे भेड़-पालन के उपयुक्त स्थान नहीं हैं। गर्म और आर्द्र जलवायुवाले स्थान में भेड़ों पर मास-मक्खियाँ (ब्लो-फ्लाई) पैदा

हो जाती हैं। अधिक बारिशवाली जगहें भेड़ों के उपयुक्त नहीं होती, वहाँ बहुत सी भेड़ें आन्तरिक परजीवी काटाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से मर जाती हैं। फिर, गर्म प्रदेश में भी उन पर मास-मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं। जिन क्षेत्रों में बारिश का पानी निकल नहीं जाता, बल्कि भूमि को गीली और कीचड़मय रखता है वहाँ इन पशुओं के पैर सड़ जाते हैं जिससे कि वे लगड़े हो जाते हैं और चल नहीं पाते। मेरिनो भेड़ के लिए बारिशवाली सबसे उपयुक्त जगह वह है जहाँ सालाना १५ से २४ इंच बारिश होती हो। अधिक बारिश बहुत अधिक वनस्पति पैदा करती है और फलस्वरूप लिकन और सफरवर्ण अधिक पैदा होते हैं। इसका एक उदाहरण न्यू साउथ वेल्स के तटीय प्रदेश सिडनी के निकट की एक जगह है जहाँकि औसत बारिश ५० इंच है और वहाँ लिकन तथा सफरवर्ण भेड़ों के लिए अच्छी चारागाह है। इन क्षेत्रों में मेरिनो भेड़ें जिंदा नहीं रह पाती, वे ५०० मील अन्दर के प्रदेशों में रहती हैं जहाँकि उनके अस्तित्व के लिए अनुकूल अवस्थाएँ हैं। मेरिनो भेड़ कर्तक हैं और वे अधिक भोजन पसन्द नहीं करती। सूखी जगहों में अर्थात् जहाँ १० इंच से कम बारिश होती है, मेरिनो भेड़ें मौत का शिकार हो जाती हैं।

भोजन का प्रभाव

चट्टानों और मिट्टी की रासायनिक रचना भेड़ों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है। कुछ भेड़ मीली लवणीय चट्टानों की खोज में चली जाती हैं, जिन्हें कि वे अपनी तृप्ति के लिए चाटती हैं और किसान उन्हें चाटने के लिए लवणीय चट्टान उपलब्ध करते हैं। हाल के अनुसंधान से पता चला है कि स्वाभाविक भूभाग में कोबाल्ट और तांबे की कमी होने पर ऊन की मात्रा और स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इन कमियों को उनके भोजन में इन लवणों को मिलाकर ही दूर किया जा सकता है। भोजन में कोबाल्ट लवण मिलाने से पशुओं की पाचन शक्ति बढ़ती है और उसे परोक्ष रूप से लाभ पहुँचता है। जब पशुओं के भोजन में प्रति दिन ०.८ मिलिग्राम

तक ताबीय लवण मिलते हैं तो ऊन का वजन बढ़ जाता है। इन लवणों की मात्रा अधिक हो जाने से ऊन पीले पड़ जाते हैं। फिर सवर्ण-लवणीय चट्टानों को उन्हें चटाकर पीलापन दूर किया जाता है। शुल्बार्कि की कमी अथवा आधिक्य से रेशे के विकास पर असर पड़ता है। मिट्टी की रचना ऊन के हस्तन रूप और उत्पादन को प्रभावित करती है। मरुभूमि अवस्थाओं में गर्म और सूखी हवाओं से उड़कर बालू भेड़ों के बालों में जा चिपकते हैं और कड़े व रूखड़े हस्तन ऊन पैदा करते हैं जोकि सूखे व गर्द भरे होते हैं। बलुआही मिट्टी चिकनी भेड़ों से सट जाती है और यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वस्तुतः कितना ऊन उत्पादन हुआ है। बालू का रंग ऊन के रंग को बिगाड़ सकता है और बहुरंगी अशुद्धियाँ चिकने बालों को अनाकर्षक बना देती हैं। ऊन का मूल उसके उस जगह की लगी मिट्टी से पता लग जाता है जहाँकि भेड़े पलती है। पश्चिमी और दक्षिणी आस्ट्रेलिया के लाल-बालू वहाँ उत्पादित ऊन का रंग ललौछ-भूरा बना देते हैं। क्वीन्सलैंड का ऊन उस क्षेत्र की विशेषता के अनुरूप ललौछ-भूरा हो जाता है। साउथडाउन ऊन का सुपरिचित और तेज हस्तक उस इलाके की चॉक-पहाड़ियों के कारण है।

मौसम का प्रभाव

वातावरण के प्रभाव पर तीन समय-क्रम में विचार किया जा सकता है (१) सदियों के वातावरण का प्रभाव, जिससे कि खास किस्म का ऊन पैदा हुआ है। (२) दशकों के वातावरण का प्रभाव जिससे खास नस्लें पैदा हुई हैं। (३) मौसम में पड़ा प्रभाव—खास मौसम में उत्पादित ऊन के स्तर पर पड़ा प्रभाव।

यथापि वातावरण से सम्बन्धित उक्त कारकों से ये परिणाम निकल सकते हैं, उन पर जहाँ वे पाले जाते हैं उसका प्रभाव होता ही है। मौसम में पड़नेवाले प्रभाव पर नस्ल विकास और पालन का बहुत प्रभाव पड़ता है और उस मौसम में पैदा हुए ऊन के स्तर पर तुरन्त प्रभाव डालता है।

कई वशों के दीर्घकालीन प्रभाव ने एक ऐसे किस्म के पशु का विकास किया है जिसकी चन्द खासियतें हैं। इन विशेषताओं के विकास पर वातावरण का ही मुख्य प्रभाव पड़ा है। ये जानवर अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देते हैं। इन निश्चित गुणों से, जोकि उन्होंने पारिस्थितिक अवस्थाओं के प्रभाव के फलस्वरूप प्राप्त किया है तथा वह वग दर वग चला आ रहा है, एक नस्ल की स्थापना हो गयी है। यह नस्ल तब तक बनी रहेगी, जब तक कि उसे उन्हीं अवस्थाओं में पाला जाता है। इस प्रकार विभिन्न देशों और जलवायु स्थितियों में पाले जाने के कारण मेरिनो, पहाड़ी आदि किस्म की भेड़ों की नस्ल बन गयी है। इस तरह के पालन ने पहले की भेड़ों में बारिश और मौसम से रक्षा करने हेतु बालों की जो दो तहें हुआ करती थी उन्हें समाप्त कर दिया है और अब सिर्फ मुलायम बाल पैदा करती है। इस प्रकार प्रकृति ने भौगोलिक स्थितियों और जलवायु के अनुरूप विभिन्न किस्म की भेड़ों को पैदा किया।

बीस से सौ वर्षों की अवधि में जो प्रभाव पड़ता है, उससे एक ही नस्ल की भेड़ों को एक ही स्थान पर, जैसे ब्रिटेन में, पालने में एक जैसे ही गुण भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण पैदा हो जाते हैं। उनके एक वश से दूसरे वश में जो भिन्नता होती है वह बड़ी सूक्ष्म होती है। वह वातावरण के अनुसार आदते और गुण विकसित कर लेती है। इससे नस्ल बनी रहती है। मनुष्य द्वारा प्रवरणशील प्रजनन प्रयुक्त करने से भेड़े प्राकृतिक और खास-खास जगहों में पाली जाने लगी हैं।

इंग्लैंड की सबसे पुरानी नस्ल की भेड़ पन्द्रहवीं सदी की काट्सवाल्ड है, जिसकी अब सिर्फ दो जातियाँ ही मौजूद हैं। अभी ब्रिटेन में ३० विशिष्ट नस्लें हैं, जिन्हें चरागाही अथवा कृषक सस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक मान्य नस्ल के लिए अलग अलग भेड़ प्रजनन समिति है, जोकि स्टॉक-बुक में उस जाति की भेड़ का पूरा विवरण रखती है ताकि नस्ल का खून शुद्ध बना रहे और मौजूद भेड़ों में कोई खराबी न आये। दर्ज पशुओं

में कोई ऐसा चिह्न लगा रहता है, जोकि उनके नस्ल की शुद्धता दर्शाता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

भेडो तथा उनके ऊन पर, उनके जीवन काल में, वातावरण का तुरन्त प्रभाव मौसमी होता है। मौसम के परिवर्तन से एक मौसम में छोटे रेशे पैदा हो सकते हैं तो दूसरे मौसम में लम्बे। इसी तरह अगर उन्हें वैसे स्थानों में ले जाया जाय, जोकि उनके लिए अधिक उपयुक्त हों, तो उनके ऊन में सुधार भी हो सकता है और प्रतिकूल जगह में ले जाये तो खराबी भी आ सकती है। कहा जाता है कि इसी कारण मेरिनो भेडे इंग्लैंड में टिक नहीं सकी। तथापि अब इस बात का प्रमाण मिलता है कि यह बिल्कुल सही नहीं है और इसका मुख्य कारण आर्थिक था। एक स्काटिश किसान ने कहा है कि मेरिनो

भेडे अपने खाने का चुनाव करती है, अतः प्रति एकड़ में कुछ ही भेडे चर सकती थी और इसीलिए उन्हें पालना अनुकूल नहीं समझा गया। तथापि इंग्लैंड के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में, यार्कशायर में भी, कई नर मेरिनो भेडे थे। भेडो को मेरिनो से परिपूरित करने के लिए टस्मानिया भेजा गया।

ससार के व्यावसायिक क्षेत्र में ऊन व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है और ऊन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्रियों में गिना जाता है। कृषिक रूप में अर्धविकसित क्षेत्रों में इसका सबसे सस्ता उत्पादन होता है। दूरस्थ स्थानों में भेज कर भी किसान इसे काफी लाभदायक पाते हैं। ससार में उत्पादित कुल ऊन का अधिकांश उत्तरी गोलार्द्ध में खपता है।

बिड़लापुर (पश्चिम बंगाल), २ जून १९६४

दिल्ली; मद्रास, बंगलोर और कलकत्ता में खादी ग्रामोद्योग की प्रतियाँ वहाँ के खादी ग्रामोद्योग भवन से प्राप्त की जा सकती हैं। भवनों के पते इस प्रकार हैं :

खादी ग्रामोद्योग भवन

१४, रीगल बिल्डिंग

कनाट सर्कस

नयी दिल्ली

खादी ग्रामोद्योग भवन

१७-१८, सिल्वर जुबली पार्क रोड

बंगलोर-२

खादी ग्रामोद्योग भवन

१९०, माउण्ट रोड

मद्रास-२

खादी ग्रामोद्योग भवन

२४, चित्तरजन एवेन्यू

कलकत्ता-१२

स्कूली बच्चों के विकास पर ताड़-गुड़ का प्रभाव

मेरी जार्ज

मद्रास राज्य के उत्तरी आर्कोट जिले में २०० लड़कों को पूरक भोजन के रूप में ताड़-गुड़ खिलाये के प्रयोग किये गये। प्रयोगों से पता चलता है कि इससे उनकी शारीरिक बाढ़ को तीव्र बनाने में सहायता मिलती है। तथापि, यह सवाल अभी शेष ही है कि आहार की कमियाँ अकेला ताड़-गुड़ किस हद तक दूर कर सकता है।

दक्षिण भारत में रहनेवाले व्यक्तियों की खुराक में पूरक भोजन के रूप में ताड़-गुड़ के आहार-मूल्य का अध्ययन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने छ महीने के लिए अन्वेषण परियोजना स्वीकृत की। नियंत्रित भोजन करनेवाले बच्चों को पूरक आहार के रूप में ताड़-गुड़ खिलाया गया और उनके शारीरिक विकास पर ऐसा करने का जो प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के लिए मद्रास राज्य के उत्तरी आर्कोट जिले में रानीपेट स्थित राजकीय 'जूनियर एंग्लो स्कूल' का चयन किया गया, क्योंकि वहाँ के सभी बच्चे देहात के थे और वे कुछ समय के लिए एक निश्चित खुराक पर रहे हैं तथा कड़े नियंत्रण के अन्तर्गत भी। अध्ययन अप्रैल १९६३ में प्रारम्भ किया गया और सितम्बर १९६३ के अन्त तक जारी रहा।

प्रयोग की योजना

१ बच्चों का चुनाव - स्कूल में ६०० विद्यार्थी थे। उनमें से प्रथम यो ही २०० लड़कों का प्रतिनिधि नमूने के तौर पर चुनाव किया गया। चुने हुए लड़कों को उनकी लम्बाई के अनुसार एक कतार में खड़ा किया गया और सर्वोच्च चयन की विधि को दूर करने के लिए एकान्तर लड़कों को छोट कर दो वर्ग-प्रयोग वर्ग और नियंत्रण वर्ग-बनाये गये।

२ ताड़-गुड़ खिलाना प्रारम्भ में यह तय किया गया कि जिन लड़कों को चुना गया, उनमें से प्रत्येक

को लगातार छ महीने तक आम तौर पर भोजन करने के बाद २८ ग्राम ताड़-गुड़ सुबह और २८ ग्राम शाम को खिलाया जाय।

३ विकास-प्रभाव जानते हेतु शारीरिक माप वजन, लम्बाई और सीने की माप साधारणतया शारीरिक विकास की कसौटी मानी जाती है। इस अध्ययन के लिए विकास-निर्देशक जानने हेतु समय-समय पर इनकी माप ली गयी। तदनुसार हर पन्द्रहवें दिन वजन और प्रत्येक तीसरे महीने लम्बाई तथा सीने की माप लेकर सबको दर्ज किया जाता था।

४ लड़कों में अध्ययन की अवधि में यदि किसी प्रकार की पौष्टिकता सम्बन्धी कमी हुई तो स्कूल के चिकित्सा अधिकारी समय-समय पर उसका विश्लेषण करते थे।

प्रस्तुत अध्ययन में शामिल लड़कों पर पौष्टिकता सम्बन्धी प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए घर तथा स्कूल में उनकी आहार सम्बन्धी पृष्ठभूमि का-और उनके पारिवारिक सम्बन्धों का भी, जिनका उनकी वृद्धि तथा विकास पर बड़ा निर्णायक प्रभाव पड़ता है-विश्लेषण करना वाछनीय है। मान्य स्कूलों में साधारणतया ऐसे पचमेल लड़कों का समाज होता है, जिन्हें बुरी आदतें होती हैं और जिन्हें उनसे बचाया जाता है तथा इसके लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए शिक्षा, सहकारी जीवन और सामूहिक भोजन के जरिये पुनर्वास की कठोर योजना के अन्तर्गत रहना पड़ता है।

इस अध्ययन के लिए जिन लड़कों का नाम शामिल किया गया, इस स्कूल के अनुशासन में उनके रहने की अवधि अलग-अलग है, जैसा कि तालिका १ में दिखाया गया है।

तालिका १

स्कूल में विद्यार्थियों के रहने की अवधि

मान्य स्कूल में व्यतीत अवधि	प्रयोग वर्ग	नियंत्रण वर्ग
१ वर्ष या कम	१४	२०
१ से १½ वर्ष	२४	२८
१½ से २ वर्ष	१३	१०
२ से २½ वर्ष	१३	१८
२½ से ३ वर्ष	१२	११
३ से ४ वर्ष	१५	१०
४ वर्ष और अधिक	०	२
शकास्पद	९	१
	१००	१००

पारिवारिक पृष्ठभूमि

उक्त लड़कों में से ७० प्रति शत से अधिक, उन पर उक्त प्रयोग शुरू करने के पहले, एक से लेकर चार वर्ष तक की अवधि से एक-मात्र स्कूल की देख-रेख में रहते थे। इस स्कूल रूपी घर में आने से पहले उनका पालन-पोषण अधिकांशतः उनके परिवारों की घोर गरीबी की अवस्थाओं और अव्यवस्था की स्थिति में हुआ था। सही जानकारी १७४ लड़कों के सम्बन्ध में मिली। उनमें से २८ को बाप का, १५ को माँ का और १८ को माँ-बाप दोनों का, मर जाने के कारण, प्यार नहीं मिला तथा १२ का तो स्कूल में दाखिला, वास्तव में, अनाथों के रूप में हुआ। बड़े-बड़े परिवारों में अधिकांश का पालन-पोषण आंशिक रूप से उपेक्षित बच्चों की तरह हुआ। इस प्रकार १९ के पाँच-पाँच, ३२ के छ-छ, २४ के सात-सात, १५ के आठ-आठ, ५ के नौ-नौ, ५

के दस-दस, १ के न्यारह और १ के १२ भाई-बहिन थे, तथा अपने परिवारों में वे सघर्षमय जीवन बिता रहे थे। इन कारणों पर एक साथ विचार करने पर पता चलता है कि इन लड़कों के किसी भी विकास अध्ययन अथवा पुनर्वास कार्यक्रम में उनकी अपनी एक प्रणाली है।

पौष्टिकता कमी के लक्षण

प्रायोगिक भोजन खिलाते रहने के पहले और वंसा करते रहने के दौरान चिकित्सक अधिकारी के मार्ग-दर्शन में पौष्टिकता के सम्बन्ध में किये गये मूल्यांकन से लड़कों में जो कमियाँ ध्यान में आयी, उनका विवरण तालिका २ में दिया गया है।

तालिका २

पौष्टिकता सम्बन्धी कमी के लक्षण

	प्रयोग से पूर्व		प्रयोग के दौरान	
	प्रयोग वर्ग	नियंत्रण वर्ग	प्रयोग वर्ग	नियंत्रण वर्ग
सूक्ष्म-शोथ	३०	१६	१	—
जीर्वा-शोथ	—	५	१	—
नेत्रग्लेबमला-शोथ	—	—	१७	४
रतौधी	२	—	—	—

आहार सिंहावलोकन

कुछ को छोड़ कर ये सभी लड़के गरीब अथवा घोर गरीब परिवारों के थे। दक्षिण भारत में लोगों के असंतुलित आहार-निम्न कोटि का चावल-से उनकी भोजन सम्बन्धी पृष्ठभूमि का पता चलता है। इस आहार में कुल कैलोरी का ८५ प्रति शत अथवा उससे भी अधिक, भाग चावल और एक या ज्यादा किम्ब के मोटे अनाज का रहता है। प्रोटीन युक्त भोजन-फिर चाहे उसका स्रोत निरामिष हो अथवा सामिष-का अनुपात बहुत ही कम है। दूध का सेवन प्रायः नगण्य है। हरी मन्जी,

दाल, फल आदि जैसे सरक्षणकारी पदार्थों का सेवन भी बहुत कम होता है। जब अनाज की कमी होती है तो टेपिओका जैसे कन्द मूल का, जहाँ-कहीं उपलब्ध हो वहाँ पूरक भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। 'जूनियर एप्रूवड स्कूल' में भर्ती होने से पहले इन बच्चों को इसी प्रकार के आधार पर अपना गुजर करना पड़ता था, जिसमें गुण और मात्रा दोनों की कमी थी।

एक से चार वर्ष तक की अवधि में स्कूल में इन बच्चों को जो खुराक दी जाती थी, उसके औसत मूल पदार्थों का वर्णन तालिका ३ में दिया गया है।

तालिका ३
स्कूल के भोजन की अनुसूची

समय	सुबह	दोपहर	शाम
गेहूँ	१४२ ग्राम	—	—
चावल	—	११३ ग्राम	८५ ग्राम
सब्जी	—	११३ ५ ग्राम	११३ ५ ग्राम
दूध (मासाहारी)	० ८१	केवल शुक्रवार को प्रत्येक को ८१ ग्राम दूध	
(शाकाहारी)	० १६२	—	—
मास	—	० ९८ ग्राम*	—
प्याज	—	७ ग्राम	७ ग्राम
भूनी हुई मूँगफली	—	—	२८ ग्राम
दाल	—	३८ ग्राम	३८ ग्राम
घी	—	१४ ग्राम†	—
केले	—	—	२ केवल शुक्रवार को
गुड़	—	—	१४ ग्राम
इमली	—	७ ग्राम	७ ग्राम
जिजली तेल	—	१५.७५ ग्राम	१५.७५ ग्राम
पिसा हुआ मसाला	—	३ ५ ग्राम	३ ५ ग्राम
नमक	७ ग्राम	९ ग्राम	९ ग्राम

* केवल मंगलवार, बुधवार और रविवार को।

† केवल बुधवार और रविवार को।

इस रोजमर्रा की औसत खुराक का प्रोटीन, वसा, कार्बोहायड्रेट और खनिज तत्वों सम्बन्धी तथा इसके दैनिक कैलोरी-तत्वों के बारे में विस्तृत विश्लेषण तालिका ४ (पृष्ठ ६८७) में किया गया है।

उक्त सघटकों के विटामिन मूल्य का हिसाब नहीं लगाया गया है, क्योंकि सप्लाई किये जानेवाले पकाये हुए भोजन का विश्लेषण नहीं किया गया है और यह भी पता नहीं है कि विभिन्न सघटकों को पकाने में तथा उनके भाण्डारीकरण में कितना नुकसान होता है।

प्रायोगिक भोजन

दक्षिण भारतवासी भूतकाल से ही अपने भोजन में ताड़-गुड़ का उपयोग करते आये हैं, यद्यपि अब धीरे-धीरे इसके स्थान पर चीनी का प्रयोग किया जाने लगा है—खास कर शौकिया कारणों को लेकर। आहार-मूल्य सम्बन्धी तालिकाओं (हेल्थ बुलेटिन २३) में गुड़ के मुख्य तत्वों का विश्लेषित मूल्य इस प्रकार दिया गया है खनिज द्रव्य ० ६ प्रति शत (कैल्सियम ० ०८ प्रतिशत, फास्फोरस ० ०४ प्रति शत, लोहा ११ ४ माइक्रो ग्राम प्रति शत)

कार्बोहायड्रेट ९५ प्रति शत

विटामिन 'ए' ० (प्रति १०० ग्राम अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयों)

कैरोटीन २८० (अन्तर्राष्ट्रीय विटामिन 'ए' इकाइयों)

विटामिन 'बी' २० (प्रति १०० ग्राम पीछे माइक्रो ग्राम)

निकोटिनिक अम्ल १ (प्रति १०० ग्राम पीछे माइक्रो ग्राम)

राइबोफ्लेविन ० (प्रति १०० पीछे माइक्रो ग्राम)

विटामिन 'सी' ० (प्रति १०० ग्राम पीछे माइक्रो ग्राम)

परिष्कृत चीनी में जहाँ सभी कार्बोहायड्रेट होते हैं, गुड़ में किसी हद तक निर्माणात्मक और सरक्षणकारी भोजन के तत्व भी होते हैं। चन्द चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगों के लिए भी गुड़ का प्रयोग करना बताया गया है, उदाहरणार्थ अनिसार, जिसके फलस्वरूप आंत्र ज्वर हो जाता है, और शैशवकालीन अतिसार आदि।

ताड़-गुड़ का उपयोग

अध्ययन की लघु कालीन अवधि में सुबह और शाम के भोजन के बाद २८-२८ ग्राम ताड़-गुड़ खाने के लिए दिया गया। बिना किसी व्यवधान के १८१ दिन तक लगातार नियमित रूप से ताड़-गुड़ खिलाया जाता रहा।

मामूली बीमारी के कारण अनुपस्थिति अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से स्कूल छोड़ देने के अपवादों को छोड़ कर लड़के भी प्रायः इस सम्बन्ध में नियमित रहते थे। ताड़-गुड़ उपभोग में नियमितता इस प्रकार रही

ताड़-गुड़ खाने के वक्त
उपस्थिति (प्रातिशत्य)

लड़कों की संख्या

१००	८४
९५ से १००	३
९० से ९५	२
८५ से ९०	१*
८० से ८५	८*
७५ से नीचे	२

१८१ दिन १०० लड़के

* प्रयोग समाप्ति से पूर्व स्कूल छोड़ गये।

अध्ययन के उत्तरार्द्ध में जिन लड़कों ने स्कूल छोड़ा उनमें से नौ प्रायोगिक लड़कों में से थे, चार नौ वर्ष के

आयु वर्ग में से थे और एक-एक अन्य पाँच वर्गों में से। सितम्बर के अन्त से पूर्व जिन्होंने स्कूल छोड़ा उनमें से १२ नियंत्रण वर्ग में से थे, एक दस-वर्षीय आयु-वर्ग में से, तीन बारह-वर्षीय आयु वर्ग में से, तीन तेरह-वर्षीय आयु-वर्ग में से और एक चौदह-वर्षीय आयु-वर्ग में से था।

शारीरिक माप

कुल २०० लड़कों—एक सौ प्रयोग वर्ग में और एक सौ नियंत्रण वर्ग में—से प्रत्येक का हर पन्द्रहवें दिन वजन लिया जाता था तथा लम्बाई और सीने की माप हरेक तीसरे महीने। बाद में आकड़ों को सारणीबद्ध करने के लिए इन लड़कों को स्कूल में दर्ज उनकी उम्र के अनुसार आयु-वर्गों में विभक्त किया गया। कुल २०० विद्यार्थियों में से १९३ छात्र ९-१५ के आयु वर्ग में थे शेष सात लड़के १६ और १७ वर्ष से कम उम्र के थे तथा उनकी संख्या नगण्य थी, इसलिए औसत निकालते वक्त उन्हें छोड़ दिया गया।

तालिका ४

स्कूल के भोजन में मुख्य तत्वों का परिकलित मूल्य
(दैनिक आधार पर सगणित)

मद	प्रोटीन	वसा	कार्बोहायड्रेड	खनिज तत्व	कैलोरी
उसना चावल	१९८ ग्राम	१२ ६७	० ७९	१५६ ६२	१ ५८ ६८५ ०८
गेहूँ	१४२ "	१६ ७६	२ १३	१०१ १०	२ १३ ४९४ १६
दाल	७६ "	१९ ०८	० ५३	४५ ३७	१ ६० २६२ ९६
भूनी हुई मूँगफली	२८ "	८ ६२	११ १०	५ ४०	० ६४ १५७ ०८
मांस (सप्ताह में तीन बार, प्रत्येक बार १४ ग्राम)	४२ "	० ७८	० ५६	—	० ०६ ० ८१
दूध (सप्ताह में सबको केवल एक दिन)	१२ ४ "	० ४१	० ४५	० ५९	० ०९ ८ ०६
सब्जी	२२७ "	७ ०४	९ ९१	१३ ७३	४ ०९ ९१ ९४
प्याज	१४ "	० १७	० ०१	१ ६२	० ०८ ७ १४
गुड़	१४ "	० ०६	० ०२	१३ ३०	० ८४ ५३ ६२
केले (सप्ताह में एक दिन, प्रत्येक को दो-दो)	—	० १५	० ०१	३ ४५	० १० १४ ५६
जिजली तेल, घी	३५ ५ "	—	३५ ५०	—	— ३३० १५
योग	६५ ९४	५२ ०१	३४१ १८	११ २१	२,१०५ ५६

प्रत्येक पक्ष के लिए दर्ज किये गये वजन का रिकार्ड उपलब्ध है, लेकिन अनुक्रमिक वाचनों का अन्तर बहुत ही कम है, इसलिए आकड़ों के अन्तिम विश्लेषण हेतु केवल त्रैमासिक औसत का ही उपयोग किया गया है। विकास अध्ययन के लिए आधार का काम देने हेतु अप्रैल के महीने में प्रत्येक आयु वर्ग के औसत वजन, लम्बाई और सीने से सम्बन्धित जो शुरू-शुरू के वाचन थे उनका उपयोग किया गया। प्रयोग और नियंत्रण वर्ग के विद्यार्थियों के वजन, लम्बाई और सीने से सम्बन्धित प्रारम्भिक, त्रैमासिक तथा छ माह की औसतों को सारणीबद्ध एवम् सलग्न किया जा चुका है। सभी वर्गों के लिए नमूने काफ़ी बड़े अथवा एक समान तक नहीं हैं, आकड़ों का किसी महत्वपूर्ण रूप में सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया गया है, क्योंकि किसी क्षेत्रीय आधार पर वजन, लम्बाई व सीने के सम्बन्ध में कोई अधिकारिक स्तर उपलब्ध नहीं है, जोकि इस प्रकार के विश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं।

अध्ययन से प्राप्त परिणामों पर गौर करने से पूरक भोजन के रूप में दिये गये ताड़-गुड़ के लाभ सामने आते हैं। प्रयोग-वर्ग के प्रायः सभी आयु-वर्गों में—९ और १४ वर्षवाले वर्ग को छोड़ कर—लड़कों के वजन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि और एकरूपता है। सम्भवतः कुछ शरीर-विज्ञान सम्बन्धी कारणों से १५ वर्ष की आयुवाले प्रयोग तथा नियंत्रण दोनों ही वर्गों के लड़कों के सितम्बर माह के औसत वजन में कमी हुई है। तथापि, सात में से पाँच आयु-वर्गों के ताड़-गुड़ खानेवाले लड़कों का औसत वजन उन्हीं के समानान्तर नियंत्रण वर्गवाले लड़कों से निश्चित रूप से ज्यादा रहा।

निष्कर्ष

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामान्य शरीर विज्ञान सम्बन्धी कारणों के अलावा अन्यथा अवस्थाओं में विकास, वजन, लम्बाई और सीने सम्बन्धी शारीरिक सूचकों के बारे में ताड़-गुड़ खानेवालों की वृद्धि दर नियंत्रण वर्गवाले लड़कों से ऊँची रही है। ताड़-

तालिका ५

ताड़-गुड़ सेवन सम्बन्धी प्रयोगों के परिणाम

आयु वर्ग	लड़कों की संख्या		औसत वजन	औसत वजन वृद्धि		औसत सीना	सीने में औसत वृद्धि		औसत लम्बाई	औसत लम्बाई वृद्धि	
	तीन माह	छ माह	(किलोग्राम)	तीन माह	छ माह	(इंच में)	तीन माह	छ माह	(इंच में)	तीन मा	छ माह
९	१०	६	१८ ७	१९ १५	२०.५५	२१ ६४	२२ ३९	२२ ५६	४४ १४	४४ ६९	४५ १३
				१८ ९०	२० ६२		२१.९५	२१ ८२		४४ ४५	४४ ९५
१०	९	७	२० ८३	२१ २८	२३ ७७	२२ ६८	२३ ४३	२४ २५	४५ ७०	४६ ३३	४६ ७६
				२१ १३	२२ ६९		२२.८१	२३ ११		४५ ८९	४६ ३४
११	१८	१७	२२ ६०	२३ ००	२४ १८	२२ ७८	२३ ३५	२३ ८८	४९ ०६	४९ ६७	५० १३
				२२.८१	२२ ९४		२३ ०४	२३ ३३		४९ ३१	४९ ६९
१२	२४	२३	२४ १५	२४ ५८	२५ ४०	२३ ०९	२३ ६८	२४ ३३	५० १८	५० ६९	५१ १४
				२४ ४३	२४ ३०		२३ ३०	२३ ७१		५० २९	५० ७५
१३	२०	१९	२४ २५	२४.६६	२५ ७८	२३ ३४	२४ ०९	२४ ३८	५० २५	५० ८०	५१ ३८
				२४ ४८	२४ ७४		२३ ६३	२३ ९५		५० ५१	५० ८९
१४	१२	११	२५ ०१	२५.४१	२५ ७७	२३ २८	२३ ९१	२४ ६८	५१ ०८	५१ ७९	५२ ०२
				२५ २१	२६ ११		२३.६६	२३ ९१		५१ ३०	५१ ६२
१५	६	६	२६ ४५	२६.८०	२५ ९०	२३ ४३	२४.०९	२४ ५९	५१ ५०	५२ २५	५२ ९६
				२६ ६८	२५ २१	२	२३ ७४	२३ ८३		५१ ७८	५२ ०६

गुड़ सस्ता है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। यह पर्याप्त, प्रचलित और बच्चों को सर्वाधिक स्वीकार्य भोजन भी है।

अध्ययन अभी अपूर्ण है, क्योंकि हम यह स्पष्ट दोष ही जानते हैं कि मौजूदा भोजन-स्वरूप में प्रोटीन, खनिज-खारक कैल्सियम-और विटामिन 'ए' तथा विटामिन ई२ की कमी है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि बच्चों से लेकर स्कूली उम्र व प्रौढावस्था तक ताड़-गुड़ किस हद तक ये कमियाँ दूर करता है। भूनी हुई नंग फली के साथ ताड़-गुड़ खाने पर कुछ अन्य दोष भी दूर होने चाहिये। वृद्धिशील बच्चों को दूध अथवा सफ़रंदा देने में अधिकाधिक रुचि लेने पर दक्षिण भारत में बिना

किसी विशेष खर्च के आहार को स्तरीय आवश्यकता का बनाया जा सकता है।

रानीपेट (मद्रास) २१ अप्रैल १९६४

सन्दर्भ

वस्तुतः मैं राजकीय जूनियर एप्रूव्ड स्कूल, रानीपेट के सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री बी. बी. मन्त्रमूर्ति, बी. ए., स्कूल के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी डाक्टर पी. सी. सोलोमन, बी. जी. आय. एम., एप्रूव्ड स्कूल के क्रिया-विज्ञान शाली (फीजिओलॉजिस्ट) श्री मोहम्मद नौरोस्दीन, एम. ए.; तथा मद्रास ताड़-गुड़ महकारी संघ के कार्यकर्ताओं की आभारी हूँ, क्योंकि उनकी सहायता और सहयोग के बिना प्रस्तुत प्रतिवेदन शायद ही तैयार हो पाता।

प्रस्तुत अध्ययन जूनियर एप्रूव्ड स्कूल के अधिकारियों के अनवरत सहयोग के कारण ही सम्भव बन पड़ा।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व क्रांतिकारी परिवर्तन की जानकारी के लिए
पढ़िए

जागृति
(साप्ताहिक)

हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित

वार्षिक ६ रुपये

अर्द्ध-वार्षिक ३ रुपये

एक प्रति १२ पैसे

प्रचार निर्देशालय

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन

'ग्रामोद्योग', बम्बई-५६

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सहकारिता प्रशासन

राज्य सहकार मंत्रियों का फरवरी १९६१ में लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन ने एक सिफारिश की थी। उसके अनुसार दो महीने बाद भारत सरकार ने “विभिन्न राज्यों में सहकारी विभागों के प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपायों” का सुझाव देने हेतु श्री वैकुण्ठ ल मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ‘लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सहकारिता प्रशासन’ उक्त समिति के प्रतिवेदन का, जिसकी तारीख २० अक्टूबर १९६१ है, ग्यारहवा अध्याय है।

आजादी हासिल करने के बाद देश में एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह हुआ है कि प्रायः सभी राज्यों में ‘पंचायत राज’ का श्रीगणेश हो चुका है। दिनांक २ अक्टूबर १९५९ को जिला परिषदों और पंचायत समितियों की स्थापना के जरिये ‘पंचायत राज’ की स्थापना करने-वाला देश में सबसे पहला राज्य है राजस्थान। इस नीति के अनुसरण स्वरूप सामुदायिक विकास खण्डों के कर्म-चारीगण पंचायत समितियों को हस्तांतरित किये गये। उसके साथ ही खंड के लिए राज्य सरकार के बजट-बटन समितियों को सौंप दिये गये। विकास अधिकारी को समिति के प्रधान के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। खण्ड स्तर पर खण्ड विकास समितियों का स्थान पंचायत समितियों ने ले लिया और वे पंचायतों के कामों का पर्यवेक्षण करने लगी।

राजस्थान के करीब एक माह बाद आंध्र प्रदेश ने २३५ पंचायत समितियों और २० जिला परिषदों की स्थापना की। तत्पश्चात् अन्य आठ राज्यों—असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर—में पंचायत राज की स्थापना हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में तत्सम्बन्धी कानून बन चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें कार्यान्वित किया जाना शेष है। केरल में कानून का प्रारूप समीक्षा के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी अधिकारियों के पास भेजा गया है। जम्मू और कश्मीर में अभी इस बारे में कानून बनाना बाकी है।

पंचायत राज की स्थापना राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के मुताबिक हुई, जिसने जनवरी १९५८ में हुई अपनी बैठक में बलवन्तराय मेहता समिति की लोक-तांत्रिक विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकृत किया। उसने पंचायत राज के निम्न बुनियादी सिद्धान्तों पर जोर दिया

क गाँव से लेकर जिले के स्तर तक यह एक त्रि-सूत्री संगठन होना चाहिए। इन तीनों संगठनों में परस्पर सजीव सम्बन्ध होना चाहिए।

ख उन्हें शक्ति और उत्तरदायित्वों का यथार्थ हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

ग अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए इन संस्थाओं को उपयुक्त साधन-स्रोत हस्तांतरित किये जायें।

घ तीनों ही स्तरों पर सभी विकास कार्यक्रम इन संस्थाओं के जरिये चलाये जाने चाहिए।

ड विकास किया जाय वह ऐसा हो कि उससे भविष्य में शक्ति तथा उत्तरदायित्वों का और अधिक विस्फुरण एवम् प्रतिनिधिकरण करने में सुविधा हो।

पंचायत राज संगठनों के कार्य

प्रत्येक राज्य को यह आजादी दी गयी कि वह अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पंचायत राज के जिस किसी स्वरूप को उपयुक्त समझे, अपनाये।

विभिन्न राज्यों में बने कानूनों में पंचायत राज संस्थाओं

के अधिकार और कर्तव्य बताये गये हैं। ग्राम स्तर पर सभी विकास कार्यों की जिम्मेवारी पंचायतों को दी गयी है। सभी सरकारी विभागों के जो विकास कार्यक्रम अब तक सामुदायिक विकास खण्ड चलाते थे, अब उन्हें चलाने की जिम्मेवारी पंचायत समितियों को बना दी गयी है। ज़िला परिषद सामान्यतः समन्वयकारी योजना बनाने वाली और पर्यवेक्षक संगठन है। तथापि, विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्थाओं के कार्यों व उनके क्षेत्र में भिन्नताएँ रही हैं। पंचायत समिति वह अभिकरण है जिसे मुख्यतः विकास योजना बनाने और विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाने का दायित्व सौंपा गया है। इन विकास कार्यक्रमों में कृषि, पशु-पालन, सहकार, कुटीर उद्योग, शिक्षा, सिंचाई, आदि को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। जहाँ तक सहकार सम्बन्धी कार्यक्रम के कार्यान्वय का ताल्लुक है इन संस्थाओं को, सहकारिता विभाग के कर्मचारी उपलब्ध करवाये गये हैं। पंचायत राज संगठन के पास, जोकि सहकारिता से भी ताल्लुक रखता है, जो कर्मचारी गण हैं उनके स्वरूप में कोई एक रूपता नहीं है। जहाँ अधिकांश राज्यों में प्रत्येक पंचायत समिति में सहकारिता निरीक्षक के दर्जे का एक-एक विस्तार अधिकारी प्रतिनियुक्त है, वहाँ आंध्र प्रदेश में एक सहकारिता उप-पजीयक प्रतिनियुक्त है, जो सहकारिता विकास अधिकारी के तौर पर काम करता है और जिसकी सहायता के लिए, खण्ड में सहकारी समितियों की संख्या व काम के अनुसार एक प्रवर अथवा अवर निरीक्षक होता है। महाराष्ट्र में पंचायत समिति के कर्मचारियों का गठन अथवा स्वरूप इस प्रकार होता है

पंचायत समितियों में विस्तार अधिकारियों के स्थानों की पूर्ति सहकारी विभाग से स्थानांतरण करने और ग्राम सेवकों को तरक्की देने के जरिये की गयी है। सहकारिता विभाग ने पंचायत समितियों में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति करने के अलावा प्रत्येक जिला परिषद में एक-एक सहायक पजीयक, सहायक सहकारिता अधिकारी और कुछ प्रशासनात्मक कर्मचारी (एक प्रधान क्लर्क, एक प्रवर क्लर्क और तीन अवर क्लर्क) भी प्रतिनियुक्त किये हैं। जहाँ अधिकांश राज्यों में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गयी है वहाँ महाराष्ट्र में जिला परिषदों में प्रतिनियुक्त किये गये सहायक पजीयकों की सेवाएँ ही पुनः सहकारिता विभाग में स्थानांतरित करने का ईरादा दीख पड़ता है।

विस्तार अधिकारियों पर नियंत्रण

हमें बताया गया कि अधिकांश राज्यों में पंचायत राज संगठनों में प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारियों पर प्रशासनात्मक नियंत्रण तो खण्ड विकास अधिकारी का और प्राविधिक नियंत्रण सहकारिता विभाग के जिला अधिकारी का रखा गया। यह भी बताया गया कि सामुदायिक विकास खण्डों में पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी वह जारी रखी गयी। जिस प्रश्न पर हमारा ध्यान गया वह यह है कि सामुदायिक विकास खण्डों में पंचायत राज संगठनों को अधिकार का हस्तांतरण करने के साथ

अ ६० हजार तक की आबादीवाली पंचायत समिति

आ ६१ हजार से १ लाख २० हजार तक की आबादी वाली पंचायत समिति

इ १ लाख २० हजार से ज्यादा आबादीवाली पंचायत समिति

१ सहायक सहकारी अधिकारी के दर्जे का एक अवर (जूनियर) विस्तार अधिकारी, और
२ एक सहायक विस्तार अधिकारी।

१ सहकारिता अधिकारी के दर्जे का एक विस्तार अधिकारी,
२ एक अवर विस्तार अधिकारी, और
३ एक सहायक विस्तार अधिकारी।

१ एक विस्तार अधिकारी, और
२ दो अवर विस्तार अधिकारी।

सहकारिता कर्मचारियों पर नियंत्रण के मामले में परिवर्तन हुए हैं या नहीं और हुए हैं तो किस हद तक ।

सांविधानिक शक्ति सौपना

प्रश्न उठता है कि क्या पञ्जीयक के सांविधानिक कर्तव्यों का भी पचायत राज सगठनों को हस्तांतरण किया गया है । गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र के अलावा अन्यत्र ऐसा नहीं किया गया है । गुजरात में, गुजरात पचायत अधिनियम १९६१ की धारा १५६ के अन्तर्गत इस प्रकार व्यवस्था है

१ बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, १९२५ अथवा फिलहाल गुजरात में लागू अन्य किसी कानून में जो कुछ भी निहित है उसके बावजूद राज्य सरकार पचायत कार्य सूची का ध्यान रखते हुए, उन शर्तों के अन्तर्गत जिन्हें लागू करना वह योग्य समझे, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा जिला पचायत और उसके अन्तर्गत तालुका पचायतों को पञ्जीयक अथवा उक्त अधिनियम अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत, जोकि आज्ञा में बताया जा सकता है, किसी भी दूसरे अधिकारी की शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य सौंप सकती है ।

२ खास कर, इस प्रकार के आदेश में निम्न विषयों के सम्बन्ध में शक्तियाँ देने की व्यवस्था हो सकती है

अ सहकारी समितियों का पञ्जीकरण,

आ सहकारी समितियों के उप-नियमों के संशोधनों को मान्यता,

इ किसी सहकारी समिति में सदस्यों को प्रवेश न देने पर सामने आनेवाली अपीलें,

ई सहकारी समितियों का रजिस्टर रखना,

उ किसी सहकारी समिति के नाम अथवा वर्गीकरण में परिवर्तन,

ऊ सहकारी समितियों को भागीदारी में शामिल होने के लिए अनुमति,

ए सहकारी समितियों की वार्षिक आम सभा बुलाने अथवा बुलाने की अवधि बढ़ाना,

ऐ किसी सहकारी समिति की विशेष आम सभा बुलाना,

ओ सहकारी समितियों के बन्द पड़ जाने पर उनकी अतिरिक्त सम्पत्ति की निकासी,

औ सहकारी समितियों के हिसाब-किताब तथा कागजात उत्तराधिकारी अध्यक्ष को देने के लिए मार्ग दर्शन ।

प्रावधान के अनुसार उल्लिखित शक्तियाँ, जहाँ तक उन सहकारी समितियों का ताल्लुक है जिनका कार्य-क्षेत्र एक जिले से कम का है और जिनकी अधिकृत हिस्सा-पूजी पाच लाख रुपये से कम है, जिला पचायतों को हस्तांतरित कर दी गयी है । ऐसी व्यवस्था रखी गयी है कि जिला पचायत जिन सहकारी समितियों को पञ्जीकृत करे वे सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श उप-नियमों के अनुरूप होनी चाहिये । जिला पञ्जीयक *सहकारिता विभाग में अपने अन्य कर्तव्य पूरी करने के अलावा, उक्त शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए जिला पचायत के प्रशासनात्मक नियंत्रण में काम करता है । हमारे पर्यवेक्षण से जिला अधिकारियों पर किसी हद तक दोहरा नियंत्रण है, लेकिन चूँकि उक्त व्यवस्था हाल ही में लागू हुई है, इसलिए उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना जल्द-बाजी होगी ।

महाराष्ट्र में जिला परिषद को प्रतिनियुक्त और इसलिए उसके प्रशासनात्मक नियंत्रण में काम करने-वाला सहायक पञ्जीयक पञ्जीकरण उप-नियमों के संशोधन और समितियों में सदस्यों को दाखिल न करने के फल-स्वरूप पैदा होनेवाली अपीलों के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रयोग करता है । कानून के अन्तर्गत जिलापरिषद के कर्तव्यों का प्रावधान इस प्रकार है ।

§ सहकारी समितियों (वे समितियाँ जिनका कार्य क्षेत्र

* जिला स्तर पर कार्य करनेवाला सहकारिता विभाग का अधिकारी ।

§ महाराष्ट्र जिला परिषद और पचायत समिति अधिनियम, १९६१-१९६२ (में संशोधित) की प्रथम अनुसूची ।

एक जिले से कम क्षेत्र में हो और जिनकी अधिकृत हिस्सा-पूजी एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं, जिन्हें आगे इस इन्दिराज में "उक्त समितियाँ" कहा जायेगा) पर व्यवसाय स्तरों में और वित्तीय स्थिति में सुधार करने तथा इस प्रकार की समितियों के सम्बन्ध में सहकारी आन्दोलन की कार्यशीलताओं का विस्तार करने की दृष्टि से केवल उक्त समितियों का सामान्य कार्य-संचालन, उनके प्रबन्ध और माली हालत का मुआयना करने की सीमा तक ही और खास कर

क उक्त समितियों के पञ्जीकरण,

ख उक्त समितियों के उपनियमों की स्वीकृति, और

ग उक्त समितियों में सदस्यों को शामिल न करने के फलस्वरूप सामने आनेवाली अपीलों पर कार्यवाही करने के काम में शीघ्रता लाने के लिए प्रशासनात्मक नियंत्रण।

अधिनियम के उक्त प्रावधान की व्यवस्था के सन्दर्भ में, जिला परिषद में नियुक्त अथवा उसके अन्तर्गत काम करनेवाले सहायक पञ्जीयक को अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्य आदर्श उप-नियमों और पञ्जीयक द्वारा प्रेषित निर्देशों के अनुसार करने पड़ते हैं तथा उसे पञ्जीयक के सामान्य मार्ग-दर्शन, अवीक्षण और नियंत्रण के अन्तर्गत काम करना पड़ता है। केवल प्रशासनात्मक मामलों में ही वह जिला परिषद के सामान्य पर्यवेक्षणान्तर्गत होता है। हमें बताया गया कि अभी हाल ही में मद्रास में विस्तार कर्मचारियों को उप-नियमों में सशोधन दर्ज करने का अधिकार दिया गया है, यद्यपि मात्र यही अधिकार देने की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है। हमने एक पञ्जीयक के साथ इस मसले पर चर्चा की। उसका विचार था कि चूँकि जिला परिषद को जो शक्तियाँ दी गयी हैं उनका इस्तेमाल आदर्श उप-नियमों के अनुसार और जिला अधिकारी के सामान्य मार्गदर्शन, नियंत्रण के अन्तर्गत करना होता है, इसलिए हो सकता है कि उक्त व्यवस्था असन्तोषप्रद न हो।

पचायत राज सस्थाओं को साविधानिक शक्तियाँ देने के सवाल का 'पचायतो और सहकारिताओं पर कार्यकारी दल' ने परीक्षण किया था। इस विषय पर दल ने निम्न विचार व्यक्त किये

शक्तियाँ देने के सवाल के स्पष्ट दो भिन्न पक्ष हैं जिनके सम्बन्ध में कभी-कभी भ्रांति हो जाती है। सहकारिताओं के सम्बन्ध में फिलहाल पञ्जीयक को कुछ साविधानिक और असाविधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह नीति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि भविष्य में पञ्जीयक की शक्तियाँ कानून में प्रदत्त शक्तियों तक ही सीमित रहनी चाहिये। इसके अतिरिक्त समय-समय पर यह भी सुझाया गया है कि इनमें से कुछ शक्तियाँ धीरे-धीरे करके सहकारी समितियों और उनके सघीय सगठनों को दे देनी चाहिये। सहकारी आन्दोलन में स्व-नियमन और बाह्यनियन्त्रण के स्थान पर स्वानुशासन की स्थापना ही सहकारिताओं का उद्देश्य है। चूँकि पचायत राज सस्थाओं को सहकारिताओं के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये, उक्त दल का इसी से ताल्लुक है, इसका वस्तुतः उन सोपानों से सम्बन्ध नहीं है कि उनके अनुसार पञ्जीयक की शक्तियाँ सहकारी व उनके सघों को दी जा सकती हैं। चूँकि पचायत राज सस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सम्बद्ध स्तरों पर सरकार के रूप में काम करेंगी, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि इन सस्थाओं को शक्ति देने का असर सहकारी आन्दोलन को स्व-नियमित करना नहीं होगा। सहकारी आन्दोलन पर जिला परिषद अथवा पचायत समिति की शक्ति उसी अर्थ में बाह्य शक्ति होगी जिस अर्थ में आज उस पर पञ्जीयक की शक्ति है। जिला परिषद और पचायत समिति को सहकारिताओं पर किस हद तक शक्ति प्रदान की जा सकती है, इसका निर्णय इसी सन्दर्भ में करना चाहिए।

प्रश्न का दूसरा पक्ष कुछ वे शक्तियाँ पचायत राज सस्थाओं को हस्तांतरित करने से सम्बद्ध हैं जिनका फिलहाल पञ्जीयक प्रयोग करता है। सम्भवतः यह

दलील दी जा सकती है कि चूकि फिलहाल सहकारी आन्दोलन पजीयक का वाह्य अनुशासन स्वीकार करता है, इसलिए यदि यह अनुशासन उपयुक्त स्तरों पर पजीयक के स्थान पर पचायत राज सस्थाओं को दे दिया जाता है तो सहकारी आन्दोलन को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिये। तथापि, इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में दो गम्भीर एतराज हैं। प्रथम, कुछ राज्यों में सहकारी आन्दोलन आत्म-निर्भर बन रहा है और शनैः शनैः राजकीय अभिरक्षण से नमस्कार कर रहा है। यदि यह प्रक्रिया विकास की वर्तमान अवस्था में निश्चलीकृत कर दी जाती है और स्थानीय सस्थाएँ सरकार के 'हिताधिकारियों' के रूप में पजीयकी शक्तियाँ अपने हाथ में लेती हैं तो इस बात की कोई आशा नहीं है कि सहकारिताएँ निकट भविष्य में ही स्व-नियमित बन जायेगी। द्वितीय, सरकारी अधिकारी के रूप में पजीयक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक प्रभाव से ऊपर उठा हुआ होगा और किसी बात के सम्बन्ध में निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनायगा। स्थानीय सस्थाओं से उपयुक्त रूप में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये भी उसी प्रकार निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनायेगी, क्योंकि उनमें स्पष्ट राजनीतिक प्रभाव होगा। और फिर, पजीयक को प्राप्त कुछ शक्तियाँ निर्वाचित सस्थाओं को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम नहीं समझते कि पजीयक की कोई भी शक्ति जिला परिषद और/अथवा पचायत समिति को हस्तांतरित करना वाछनीय होगा। पजीयन, प्रबन्ध समिति को बर्खास्त करना, उप-नियमों की स्वीकृति और उनमें संशोधन, सदस्यों पर 'सरचार्ज' लगाना, मध्यस्थता और परिसमापन स्पष्ट अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ हैं एवम् पजीयक के पास ही रहनी चाहिये। लेखा-परीक्षण भी पजीयक का साविधानिक कर्तव्य है, जो वह विशिष्ट योग्य कर्मचारियों के जरिये पूरा करता है तथा वह निर्वाचित सस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

(अध्याय ६, पैराग्राफ ९ से ११ तक)

* * *

कानून अथवा नियमों में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि सदस्यता के लिये आवेदन-पत्र पर उसकी प्राप्ति से १५ दिन के अन्दर-अन्दर विचार किया और स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये। यदि किसी व्यक्ति को सदस्य न बनाने का निर्णय किया जाता है तो उसके कारण दर्ज किये चाहिये तथा १५ दिन के भीतर प्रार्थी को बताये जाने चाहिये। यदि इस अवधि में कोई निर्णय प्रार्थी तक नहीं पहुँचाया जाता है तो यह मान ही लेना चाहिये कि इन्कार कर दिया गया है तथा एक निश्चित अवधि में अपील करने का अधिकार प्रार्थी को होना चाहिये। अपील कर देने पर सम्बद्ध उत्तरदायी सहकारी अधिकारी को चाहिये कि वह एक माह की अवधि में अपील पर फैसला कर दे। हम नहीं सोचते कि अपीलों पर सुनवाई करने के सम्बन्ध में शक्तियाँ पचायत राज सस्थाओं को दे देने से तत्सम्बन्धी प्रक्रिया सरल अथवा ज्यादा प्रभावशाली हो जायेगी।

(अध्याय ६, पैराग्राफ १४ और १५)

* * *

जिला परिषद जैसी निर्वाचित सस्था को साविधानिक शक्तियाँ देने के प्रभाव का मूल्यांकन करना, अभी जल्दबाजी होगी। तथापि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की वाह्य शक्तियों को आवश्यक रूप से ही व्यावसायिक सगठनों-सहकारी समितियों-के कार्य-संचालन को प्रभावित न करने दिया जाय। इस सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिये कि उनकी कार्यकुशलता और ठोसपन पर किसी प्रकार की आच न आये तथा उनकी स्वायत्तता सुरक्षित बनी रहे। और फिर, पचायत राज सस्थाओं को शक्ति के हस्तांतरण से सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी हल्की हो जायेगी तथा उन सस्थाओं को शक्ति का हस्तांतरण करने की दिशा में प्रगति में रोड़ा आ जायेगा, जोकि आन्दोलन को स्वानुशासित और स्वनियमित बनायेगी। इन विचारों की पृष्ठभूमि में हम 'पचायतो और सहकारिताओं पर कार्यकारी दल'

के विचार से सहमत है कि पजीयक की कोई भी सा-विधानिक शक्ति पचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना वाछनीय नहीं है। इस विषय पर तृतीय पंच वर्षीय योजना में व्यक्त विचारों से भी, जिन्हे हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं, हमारे कथन की पुष्टि होती है

ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन और सघन विकास करने के सम्बन्ध में पचायत राज संस्थाओं तथा सहकारिताओं की भूमिका प्रत्येक कदम पर निकट रूप से परस्पर एक-दूसरी की पूरक है। जिला परिषदों, पचायत समितियों और ग्राम पचायतों को चाहिये कि वे सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहन दे तथा सामुदायिक प्रयास और सामाजिक उत्तरदायित्व का वातावरण निर्मित करने की कोशिश करें, जोकि सभी स्तरों पर सहकारिताओं के सफल मंचालन के लिए अत्यावश्यक है। सहकारी सगठनों के सम्बन्ध में नियामक शक्तियाँ सरकार के पास रह सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ शक्तियाँ उत्तरोत्तर रूप से सघीय सहकारी सगठनों को दी जा सकती हैं। इससे आन्दोलन की स्व-नियामक विशिष्टता का निर्माण करने और स्थानीय अगुआई को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।

(अध्याय १३ पैराग्राफ ३६)

* * *

प्रोत्साहक गतिविधियाँ

पूर्वोलिखित तीन राज्यों को छोड़ कर सभी राज्यों में, हमें बताया गया कि पचायत राज संस्थाओं को केवल प्रोत्साहक कार्यशीलताएँ ही सौंपी गयी है (उदाहरणार्थ सगठन और समितियों पर सामान्य पर्यवेक्षण) तथा उन्हें कोई साविधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। तथापि सहकारिता विभाग पचायत समितियों के क्षेत्र में जांच, निरीक्षण, मध्यस्थता, डिग्री परिसमापन कार्य के लिए विस्तार कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करते हैं और इससे यह दावा किया जाता है, क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन

में विकास अधिकारी का स्थान बढ़ गया है।

पचायत समितियों जिन विकास कार्यों को हाथ में लेगी, उनके क्षेत्र से कुछ स्थानों पर भ्राति पैदा हो गयी है। हमें बताया कि कुछ पचायत समितियों का यह विचार है कि विकास कार्यों में सहकारी समितियों से वकाया की वसूली करने का काम शामिल नहीं होना चाहिये तथा यह कि यदि विस्तार कर्मचारियों को वसूली करने के काम में मदद देने का काम सौंपा गया तो ऐसा करने का विकास पर बुरा असर पड़ेगा। इससे उन क्षेत्रों में एक गम्भीर और कठिन स्थिति पैदा हो गयी है जहाँ पर्यवेक्षण का काम सहकारिता विभाग के पास है और पर्यवेक्षण के लिए विभाग के पास अलग कर्मचारी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में अतिदेय को प्रश्रय मिला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन स्थानों में वसूली करने के काम की अवहेलना की गयी है। ऐसे भी उदाहरण सामने आये कि सहकारिता विभाग के जिला अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी के मध्य, जिनका सहकारी विस्तार अधिकारी पर प्रशासनात्मक नियंत्रण है, संयोजन का अभाव है। जबकि सैद्धान्तिक रूप में सहकारिता विभाग सहकारिता विस्तार कर्मचारियों पर तकनीकल नियंत्रण रखता है, व्यवहार में वह कोई नियंत्रण नहीं रख सका। यह भी मालूम हुआ है कि चन्द क्षेत्रों में सहकारिता विस्तार अधिकारी की सेवाएँ कई अन्य कार्यों में उपयोग की गयी। ऐसे भी कई उदाहरण मिले हैं कि समितियों के सहकारिता विभाग के जिला अधिकारी द्वारा खण्ड क्षेत्रों में जांच करते वक्त विस्तार कर्मचारी अनुपलब्ध रहे हैं।

चन्द राज्यों में यह धारणा बन गयी कि सहकारिता विभाग इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम और खण्ड स्तर पर अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण खो बैठा है। चूँकि विभाग ने निम्न स्तरों पर काम करनेवाली सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण के लिए अलग से कर्मचारी नहीं रखे, उनके काम से उसका सम्पर्क टूटता नजर आया। अतः जहाँ तक सहकारिता का सम्बन्ध है, पचायत राज

सगठनों की तत्सम्बन्धी भूमिका की उपयुक्त व्याख्या करना आवश्यक होगा। हमारे विचार से इन सगठनों को प्रसार, विकास और आयोजन जैसे कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहिए। हमारे मतानुसार उन्हें नयी समितियों के पजीकरण के प्रस्ताव बनाने चाहिये, वर्तमान समितियों के सदस्यों की सख्या बढ़ानी चाहिये, कमजोर सस्थाओं को प्राणवान बनाना चाहिये, उत्पादन योजनाएँ तैयार करनी चाहिये तथा ऋण, बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिये। इन कामों में सहकारिता विस्तार कर्मचारियों की सेवा भी ली जानी चाहिए। जहाँ प्राथमिक सस्थाओं के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग की है, वहाँ उस कार्य के लिए सहकारिता विस्तार अधिकारी उपलब्ध होना चाहिये। ऋण वसूल करने के काम में सहायता देने से विकास कार्यों में बाधा पहुँचेगी, इसके लिए कोई कारण नजर नहीं आता। यदि सहकारी समितियों को ठोस व्यावसायिक सस्थाओं में विकसित होना है तो सदस्यों में अपने काम को जिम्मेदारी के साथ तथा समय पर पूरा करने की आदत डालने का प्रयास किया जाना चाहिये। जिला परिषदों और/अथवा पंचायत समितियों के कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर नियंत्रण के लिए सहकारिता विभाग के जिला अधिकारी और पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच पूर्ण समझदारी होनी चाहिये। जबकि समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकेन्द्रित रचना के अन्तर्गत

सामान्य प्रशासन पद्धति के अनुसार विस्तार कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जारी रख सकता है, उसके लिए जिला स्तरीय सहकारी विभाग के अधिकारी के आदेशों का पालन विस्तार कर्मचारियों की मदद से करना अनिवार्य कर देना चाहिए।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

सहकारिता विभाग के सामान्य और लेखा परीक्षण अनुभागों के बीच अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानान्तरण होते रहने को हमने बड़ा महत्व दिया है। हमने यह सिफारिश की है कि किसी भी ऐसे कर्मचारी को लेखा-परीक्षण का काम नहीं सौंपा जाना चाहिए, जिसे सामान्य अनुभाग के काम का कम से कम दो साल का अनुभव न हो। चूँकि विकेन्द्रित सगठन के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के अराजपत्रित क्षेत्रीय कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा पंचायत समितियों के साथ रहेगा, अतः पंचायत राज सगठनों के सुपुर्दे किये गये कर्मचारियों के स्थानान्तरण का सहकारिता विभाग को पूर्ण अधिकार होना चाहिए ताकि हमारे सुझाव कार्यान्वित किये जा सकें। इस तरह के स्थानान्तरण से पंचायत समितियों के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारियों के जो स्थान हैं उन पर ऐसे व्यक्तियों को आसीन करना सम्भव हो सकेगा जो कि लेखा-परीक्षण का अनुभव रखते हैं और इससे वे अपने विधिविहित उत्तरदायि बो के साथ साथ विकास सम्बन्धी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह निभा सकेंगे।



विस्तार पद्धतियों का प्रयोग

सोमसुन्दरम् शनमुगम्

ग्रामीणों में बुनाई उपदान योजना को प्रचलित करने हेतु विस्तार तकनीकों और पद्धतियों का उपयोगी प्रयोग किया जा सकता है।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने ६ अप्रैल १९६४ से खादी उत्पादन की अवस्था में ही उपदान देने की नयी योजना लागू की है। इस नयी योजना के फलस्वरूप उन सूतकारों को सिर्फ परिश्रम के बल पर ही खादी मिल जायेगी जोकि कताई में अपनी ही रई का इस्तेमाल करते हैं। गाँवों में रहनेवाले अन्य व्यक्तियों को भी खादी अपेक्षतया सस्ती ही मिलेगी। आशा है कि इस नयी पद्धति के लागू होने से गाँवों में खादी का बाजार बढ़ेगा और सूतकार, बुनकर तथा ग्रामीण खादी पहन सकेंगे।

गाँधीजी ने इस बात पर जोर दिया था कि खादी तभी स्थायी महत्व प्राप्त कर सकेगी जबकि ग्रामीण इसे अपना वस्त्र समझ कर इस्तेमाल करेंगे। निस्सन्देह यह नयी योजना इस उद्देश्य की पूर्ति में मदद देगी।

कार्यक्रम का समझना आवश्यक

बुनकर और सूतकार खादी कार्यक्रम के आध्यात्मिक, नैतिक आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों को समझने में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए यह काम दूसरों द्वारा मजदूरी पर दिया गया काम है। जब उन्हें दूसरे काम में अधिक मजदूरी मिलने लगती है तो वे चरखा चलाने में रुचि नहीं लेते। दिसम्बर १९६३ के खादी ग्रामोद्योग में श्रीवैकुण्ठ ल मेहता अपने लेख 'बुनाई उपदान योजना के निहितार्थ' में लिखते हैं,—“कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य काम देने के अलावा लोगों के कला-कौशल का उपयोग और विकास करना है, अर्ध और पूर्ण बेकारों को काम दे उत्पादक

कार्यों का सगठन कर अत्यावश्यक उपभोक्ता सामग्री प्रदान करना है तथा वस्त्र खरीदने में गाँव का पैसा जो बाहर जाता है उसे कम करना है एवं इस प्रकार खादी आन्दोलन का एक पहलू ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, जिसे अब तक लोगो ने अच्छी तरह नहीं समझा है।” ग्रामीण जनता के कल्याणार्थ प्रयत्नशील कार्यकर्ताओं के समक्ष यही असल समस्या है। इसके समाधान में विस्तार पद्धति सहायता देगी। सूतकार और बुनकर इस नये कार्यक्रम में सक्रिय रुचि ले सकेंगे बशर्ते कि वे इसे अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। ग्राम समाज को खादी कार्यक्रम के लाभ समझा कर उत्साहित किया जा सकता है।

विस्तार पद्धतियाँ

गाँवों में आम तौर पर यह देखा जाता है कि जब किसान को फसल कटाई के बाद पहला उत्पादन मिलता है तो वह बहुत खुश होता है। परिश्रम का फल प्राप्त होने पर प्रत्येक किसान परिवार में खुशी की यह लहर देखी जाती है। अत यदि हम सूतकारों, बुनकरों और ग्रामीणों को अपना उत्पादन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें तो खादी की बिक्री में जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें भी कम करना मुश्किल नहीं होगा। इसकी प्राप्ति का एक रास्ता यह है कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों का दल अपने उत्पादनों का इस्तेमाल कर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें।

विस्तार प्रक्रिया किसानों और अन्य ग्रामीणों को शिक्षित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है लोगों

की आदतों और व्यवहारों में परिवर्तन लाना। ग्रामीणों को शिक्षित बनाने में यह बात शामिल है कि उन्हें नये ज्ञान की क्षमताओं के प्रति आश्वस्त कर दिया जाय ताकि वे उसे अपनी क्रियाशीलताओं में प्रयुक्त कर सकें। ग्रामीण वयस्कों को सुधरे तरीके के लाभों के प्रति तभी आश्वस्त किया जा सकता है जबकि उनका प्रसार विस्वा-सोत्पादक ढंग से किया जाय। विस्तार कार्यक्रम का भौतिक उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि लाना। इस विस्तार कार्यक्रम के शैक्षणिक उद्देश्य हैं लोगों का ज्ञानवर्द्धन करना, उनके द्वारा इन्फेमाल की जानेवाली तकनीकों अथवा उनके कौशल में सुधार लाना तथा परम्परागत एवं गतिहीन पद्धतियों को छोड़ वैज्ञानिक और गतिशील प्रक्रियाएँ अपनाने में उन्हें मदद देना। इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्राम समाज के लिए कोई बाहरी दल अथवा अभिकरण काम करे।

विस्तार प्रक्रिया का सार है— व्यक्तियों को इस योग्य बनाना कि वे स्वयं निर्णय ले सकें। विस्तार पद्धतियाँ वे अवस्थाएँ निर्मित करने के उपाय हैं जिनमें कि सीखनेवाले अर्थात् किसानों या ग्रामीणों और विस्तार कर्मचारियों के बीच सम्पर्क स्थापित हो सके। ग्रामीण देख, सुन और करके ही सीखते हैं। यहाँ एक कहावत उद्धृत करना उपयुक्त होगा—“सुनी हुई बात याद नहीं रहती, देखी हुई रहती है और की हुई समझ में आ जाती है।” अतः वैसी अवस्थाएँ बनाना आवश्यक है, जिन्हें लोग देखें, सुन और अपना सकें। सभी विस्तार कार्यों में हमें ये बातें अपनानी ही चाहिये (१) सतर्कता, (२) रुचि, (३) विश्वास, (४) काम, और (५) सतोष।

हमारी समस्या है ग्रामीणों को अपने गाँव के उत्पादनो के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना। यदि व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, यदि उसे समस्या पर ध्यान देने के लिये समझाया जाता है, यदि उसका विश्वास प्राप्त कर लिया जाता है, तो वह कार्य करने के लिए उत्साहित हो जायगा। सामान्य-तया विस्तार कर्मचारियों द्वारा अपनायी जानेवाली

विस्तार पद्धतियाँ ये हैं (१) लोगों से व्यक्तिगत, दलीय और सामाजिक सम्पर्क, (२) प्रक्रियाओं और परिणामों का प्रदर्शन, (३) सिनेमा, चार्ट, पोस्टर, प्रदर्शनी आदि के जरिये लोगों में प्रचार, (४) गीत तथा नाटक और (५) पर्चे, परिपत्र आदि।

खादी और ग्रामोद्योगों की योजनाओं को समझाने के लिए ग्रामीणों से व्यक्तिगत अथवा दलीय प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना सर्वाधिक उत्तम विस्तार पद्धति है। उत्पादन केन्द्रों और बिक्री भण्डारों में काम करनेवाले कर्मचारियों को इस नयी योजना के लाभ सूतकारों, बुनकरों और शहरी ग्राहकों को समझाने होंगे।

कारीगरों के लिए अध्ययन शिविर

प्रक्रिया और परिणाम प्रदर्शन के अन्तर्गत खादी उत्पादन केन्द्रों के अधीक्षक कर्मचारियों को गाँवों के बुनकरों और सूतकारों को कताई-बुनाई के योग्य तरीकों से परिचित कराने के लिए एक-दिवसीय अध्ययन शिविरों का आयोजन करना होगा। इनमें दक्ष सूतकारों और बुनकरों को प्रदर्शन करने के लिए कहा जाना चाहिये। इनमें सूतकारों और बुनकरों को यह भी बताया जाना चाहिये कि कपास उगाने तथा सूत कातने, सिर्फ कताई करने अथवा न कपास उगाने और न कताई करने वाले ग्रामीणों को खादी किस कीमत में मिलेगी। एक शिविर में २५ व्यक्तियों से अधिक को शामिल नहीं करना चाहिये।

दलीय विचार-विमर्श पद्धति के अन्तर्गत गाँव के सभी प्रभावी नेताओं, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस नयी योजना का कार्यान्वित करने हेतु एक होने के लिए समझाया जा सकता है। इन नेताओं की मदद से कर्मचारियों को वैसा वातावरण बनाना होगा जिसमें ग्रामीण गाँव में ही तैयार किये गये वस्त्र को धारण करने के लिए प्रेरित हो सकें। अशिक्षितों को शिक्षित करने के सर्वोत्तम साधन हैं—सिनेमा, तस्वीरें, पोस्टर, गीत, नाटक, आदि।

राजेन्द्रनगर (हैदराबाद) . २७ दिसम्बर १९६३

गोबर गैस संयंत्र : एक अध्ययन

एस. डी. तेज नारायण और राब मूर्ति

आंध्र प्रदेश स्थित राजेन्द्रनगर के ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्र में गोबर गैस संयंत्र पर जो प्रयोग किये गये, इस लेख में उनका विश्लेषण किया गया है।

राजेन्द्रनगर के ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्र में एक गोबर गैस संयंत्र १९५७ में स्थापित किया गया। गैस घर (गैस-होल्डर) का व्यास ५ फुट था और ऊँचाई ४ फुट, गैस घर के तल के नीचे पाचित्र की गहराई ८ फुट थी और व्यास था ६ फुट (शीर्ष पर ६ फुट और उसके ५ फुट नीचे ४ फुट)।

ग्राम सेविका प्रशिक्षार्थियों के एक कुटीर से १०० फुट और प्रशिक्षण केन्द्र के पुराने सामूहिक भोजनालय से करीब ४० फुट की दूरी पर यह गैस संयंत्र स्थापित है। इस रसोई घर से लगा हुआ एक वस्तु भण्डार भी है, जोकि गैस संयंत्र से करीब ३० फुट दूर है। यह संयंत्र पहले पुराने रसोई घर से सम्बन्धित था और कुछ दिनों तक इससे उत्पन्न मिथेन गैस से भोजन भी बनाया गया था। परन्तु अधिक दिनों तक वैसा नहीं हो सका। बाद में स्वतंत्र कुटीरों के निर्माण किये जाने पर यह रसोई घर बन्द कर दिया गया और तत्पश्चात् संयंत्र सिर्फ प्रदर्शन के काम आने लगा।

गैस उत्पादन

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री श्री सुरेन्द्र कुमार दे ने ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करने वक्त यह सुझाव दिया कि गाँवों में गैस संयंत्र लगाया जाना सम्भव है अथवा नहीं, इसका पता लगाया जाय। फलस्वरूप सबसे निकट के कुटीर

से गैस संयंत्र की नली जोड़ कर इसका संचालन आरम्भ किया गया। अक्तूबर १९६२ में सिर्फ ६ दिन तक कुल ५½ घण्टे यह संयंत्र चला, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है

दिनांक	संयंत्र चालन (घण्टे)	कुल गैस उत्पादन (घन फुट)	गैस उपभोग (घन फुट)	प्रति घण्टा उपभोग (घन फुट)
१६-१०-६२	१	१८	१६	१६
१७-१०-६२	१½	२०	१९	१२
१८-१०-६२	१½	१८	२५	१७
१९-१०-६२	½	१३	४ ५	१३
२०-१०-६२	½	६ ५	६ ५	१३
२१-१०-६२	½	१०	५	१०

बाद में संयंत्र में कई दोष होने से उसे चलाया नहीं जा सका। चन्द प्रयोग करने के लिए पुनः उस संयंत्र को ४ जुलाई १९६३ से चलाया गया

संयंत्र की टकी की क्षमता १०० घन फुट मल-मूत्र घोल समाने की है और उसे १२० पौण्ड गोबर में उतना ही पानी मिला कर भरा जा सकता है। ग्राम सेविकाओं को दूधारू मवेशियों (कुल २०) से गोबर मिल जाता है। प्रत्येक मवेशी से दैनिक करीब ३० पौण्ड गोबर प्राप्त होता है। इस प्रकार रोजाना ६०० पौण्ड गोबर उपलब्ध

हैं। गैस उपयोग की मात्रा का पता ड्रम पर लगे पैमाने से लगाते हैं, जिसमें १ इंच भाप १ ६० घन फुट गैस का उपभोग दर्शाती है।

संयंत्र में संशोधन

जुलाई माह में यह पाया गया कि गैस छ्वातार तथा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती और प्रथम दिन प्राचार्य को यह सुझाव दिया गया कि संयंत्र में ये सुधार किये जायें (१) चूल्हे (बर्नर) और गैस संयंत्र की दूरी पुराने रसोई घर के वस्तु भण्डार से, जोकि ३० फुट दूर है, इसकी नली जोड़ कर कम की जाय। यह सुझाव भार को कम करने के लिए है। (२) वर्तमान गैस प्रदायक नलिका की जगह ऊपर में पोलीथीन नलिका लगायी जाय। यह इसलिए कि धातु नलिका होने तथा इसके जमीन के अन्दर होने से ताप और दबाव में जो अन्तर आ जाता है, वह न आये और अधिक समय के लिए स्थानीय जलवायु ग्रहण करने योग्य यह बन सके। एवम् नलिका के अन्दर पानी की बूंदें जमने से रोक सके। (३) टोटी गैस-संयंत्र के निकट ही लगी थी, जिसका काम था नलिका में से जल-कणों को बाहर करना।

लेकिन वह काम हो नहीं पाता था, क्योंकि वह नलिका के अन्त में नहीं थी और न ही चूल्हे (बर्नर) से निकटतम दूरी पर थी। अतः यह सलाह दी गयी कि नलिका के अन्त में टोटी लगायी जाय ताकि नलिका में जमा हुए जल-कणों को बाहर निकाला जा सके और गैस सहज ही प्रवाहित हो सके। गैस-घर जस्ते की नलिका से जुड़ा था, जिसका जलाधार रबड़ का था। सुझाव दिया गया कि इसके बदले भी पोलीथीन नलिका लगायी जाय।

एक प्रयोग

दिनांक ८ जुलाई १९६३ को निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि टोटी लगाना छोड़ कर बाकी सब सुधार कर दिये गये हैं और फलस्वरूप गैस-घर से प्राप्त गैस चूल्हे को काफी समय तक मिलती रही।

एक कुटीर में रहनेवाली सभी ग्राम सेविकाओं के लिए भोजन बनाने का प्रयोग किया गया। यह प्रयोग चार दिनों तक चला, जिसका विवरण निम्न है

७ जुलाई १९ मिनट	६ व्यक्तियों के लिए कॉफी बनायी गयी।
८ जुलाई सवा घण्टा	६ व्यक्तियों के लिए भोजन तैयार किया गया (२ सेर चावल और तरकारी)।
९ जुलाई २ घण्टे	४० व्यक्तियों के लिए चाय बनायी गयी और ६ व्यक्तियों के लिए एक कूकर में खाना बनाया गया।
१० जुलाई ५ १/२ घण्टे	६ व्यक्तियों के लिए कॉफी तथा कूकर में दोनों वक्त भोजन तैयार किया गया।

इन प्रयोगों से निम्न परिणाम निकले, जोकि गैस उपभोग के मामले में पूर्णतः विश्वस्त नहीं है, क्योंकि प्रति घण्टे गैस-उपभोग में बड़ी भिन्नता पायी गयी।

दिनांक (जुलाई)	गैस उपभोग (घन फुट)	समय	प्रति घण्टा उपभोग (घन फुट)
७	६ ४	१८ मिनट	२० ००
८	० ८०	सवा घण्टा	१० ६४
९	४ ४	२ घण्टा	२ २०
१०	३२ ००	३ १/२ घण्टा	१० ००

प्रति घण्टा गैस उपभोग में उपर्युक्त भिन्नता स्पष्टतः इस कारण है कि विभिन्न कारणों से गैस-घर में हुए गैस-घटाव के माप-अंकन में किसी न किसी प्रकार की कोई गलती हुई। यह देखा गया कि गैस-घर और पैमाने की गति में चन्द्र चरण होने से गैस-उपभोग के साथ-साथ

पैमाने की सूई खिसक नहीं पायी। अक्तूबर माह में उपभोग का माप काफी ठीक रहा और छ व्यक्तियों के लिए एक दिन में भोजन तैयार करने में प्रति घंटा १५ घन फुट गैस-उपभोग हुआ।

गैस उत्पादन

गैस-घर की गति के दोषों में और सुधार करने तथा पैमाने के सही अंकन के पश्चात् सम्भवतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि छ व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने हेतु प्रति घण्टा १३ घन फुट गैस की जरूरत है। सामान्यतया छ व्यक्तियों के लिए दोनों समय का भोजन बनाने में करीब ३ घण्टा समय लगता है। अतः ३९ घन फुट गैस की जरूरत होगी, जिसकी पूर्ति इस गैस-घर की क्षमता के अन्दर है, क्योंकि यदि सयत्र

के छोटे-छोटे दोषों को दूर कर दिया जाय तो वह १०० घन फुट गैस उत्पादन कर सकता है। इस तरह एक साथ दो चूल्हे जल सकते हैं। मुख्य बाधा थी दूरी की, जिसे अब प्रयोग कर दूर किया जा चुका है। अन्य लघु दोषों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और उनके बाद अन्य प्रयोग किये जायेंगे।

अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाँच फुट व्यास और चार फुट ऊँचाईवाला गैस घर ३३ फुट दूर अवस्थित आठ फुट गहरे और चार फुट व्यासवाले हौज की मदद से छ व्यक्तियों के परिवार का सारे दिन के लिए भोजन तैयार करने हेतु गैस प्रदान कर सकता है और इस कार्य के लिए चार घण्टे सयत्र का चालन करना होगा।

राजेन्द्रनगर (हैदराबाद) २ सितम्बर १९६३

पाठकों से

पाठकों से निवेदन है कि श्रद्धादी ग्रामोद्योग के न मिलने अथवा देर से मिलने के सम्बन्ध में शिकायत भेजते समय वे पते के साथ ही अपनी ग्राहक-संख्या लिखना न भूले। जैसा कि हम चाहते हैं, ग्राहक-संख्या लिखने पर यथा शीघ्र कार्यवाही करने में सहायता मिलती है।

—सम्पादक

प्रचार की निरर्थकता*

सुभाष चन्द्र सरकार

“संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य है अन्तर्-आत्मा के विरुद्ध मनुष्य के मन को मोड़ना।” ब्राउन ने अपनी सूचनाप्रद और विचारोत्तेजक पुस्तक में (पृ. २२२) उक्त बात कही है। वे लिखते हैं, “कुटिल इरादे से मनुष्य के दिमाग में वैसे विचार या भाव अधिष्ठित कर देने का विचार जोकि उसकी सामान्य विचार-प्रणाली के विपरीत हो, वस्तुतः हास्यास्पद है” (पृष्ठ २२१)। इस पुस्तक में मुख्यतः इसी बुनियादी आधार की विस्तृत व्याख्या की गयी है। इस बुनियादी कथन की पुष्टि के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध, राजनीतिक प्रचार, व्यावसायिक विज्ञापन तथा दिग्भ्रान्त (ब्रेनवाशिंग) करने के प्रयास जैसे प्रचार के विभिन्न क्षेत्रों से बहुतांश प्रमाण इसमें इकट्ठे किये गये हैं। उक्त कथन, जोकि फ्रायड के मनोविज्ञान में निहित है, मूलतः ब्राउन का नहीं है, परन्तु उनकी व्याख्या उद्देश्यपूर्ण, सूचनात्मक और दिलचस्प है। आज के “प्रचार युग” में रहनेवाले बहुत-से लोगो के लिए, जिन्हें कि प्रचार और विज्ञापन के अमित शक्ति-व के प्रति प्रभावित किया गया है, इस पुस्तक का निष्कर्ष आश्चर्यचकित करने तथा सदमा पहुँचानेवाला होगा। तथापि, इसे हृदयगम करना होगा।

यद्यपि ब्राउन प्रधानतः प्रचार के यात्रिक पहलू के बदले उसके मनोवैज्ञानिक पहलू और प्रभाव से सम्बन्धित है तथापि उन्होंने प्रचार के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किये जानेवाले आम तरीको में से कुछ का विस्तृत विवरण

दिया है। जहाँ तक तकनीक का सम्बन्ध है, दैनिक समाचार-पत्र के सजग पाठको के ताज्जुब करने लायक उसमें कोई खास बात नहीं है।

दिग्भ्रान्त करना

कोरिया में अमेरिकी बन्दियों के साथ चीनियों ने जो व्यवहार किया, उससे इस अशुभ शब्द ‘दिग्भ्रान्त करना’ (ब्रेनवाशिंग) का जन्म हुआ, जिसका सर्वप्रथम अमेरिकी पत्रकार एडवर्ड ह्यूटर ने इस्तेमाल किया। मनोवैज्ञानिक और क्रियात्मक रूप में ‘दिग्भ्रान्त करना’ शब्द अर्थरहित और बिल्कुल अवैज्ञानिक कल्पना है, क्योंकि मस्तिष्क के तंतुओं को क्षति पहुँचाये बिना याददाश्त को खत्म नहीं किया जा सकता। मनुष्य है तो स्मृतियाँ रहेगी ही और प्रत्येक सामान्य मनुष्य में चन्द स्मृतियाँ तो उसके दिमाग का अंग ही बन जाती हैं अन्यथा उसे मानसिक बीमारी हो जायेगी। चीनी साम्यवादियों ने युद्धबंदियों को वैचारिक और राजनैतिक रूप से परिवर्तित करने के लिए जो बेमिसाल कदम उठाया, उसी के कारण यह शब्द दूषित हो गया। चन्द अमेरिकी लोगो पर इससे जो सफलता मिली, उसने इसकी बड़ी प्रभावकारी शक्ति के सिद्धांत को प्रामाणिकता प्रदान की। तथापि, यदि इसके प्रभाव को इससे गुजरनेवाले लोगो के दृष्टिकोण और रुख में होनेवाले किसी स्थायी परिवर्तन की दृष्टि से मापा जाय तो व्यवहार में ‘दिग्भ्रान्त करना’ बहुत ही असफल सिद्ध हुआ है।

* टेकनीक्स ऑफ परसुएशन (फ्राम प्रोपगंडा टु ब्रेनवाशिंग), लेखक .जे.ए.सी. ब्राउन, पैग्विन बुक्स, मिडलैक्स (इंग्लैंड), १९६३, पृष्ठ ३२५, मूल्य ४ शिलिंग ६ पेन्स।

चीनियों के आग्रह से जो साम्यवादी हो गये तथा जिन्होंने उनसे सहयोग करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया, उन युद्धबंदियों की पृष्ठभूमि बड़ी रुचिकर है,

क्योंकि वह व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। साम्यवाद अपनानेवालों में से अधिकांश का अपने भूतपूर्व जीवन में किसी से कोई मजबूत सम्बन्ध नहीं बना था अथवा वफादारी कायम नहीं हुई थी। जिन्होंने सहयोग करने से दो-टुक इन्कार कर दिया, वे दो श्रेणियों में आते हैं (अ) परिपक्व और सतुलित मस्तिष्कवाले व्यक्ति, जिनमें आत्मसम्मान की बेजोड़ भावना है, और (आ) यहाँ तक कि अपने देश में भी किसी भी प्रकार के अधिकृत व्यवहार से काफी समय से मोर्चा लेनेवाले व्यक्ति। दुश्मन प्रवेशन से प्रभावशाली प्रतिरक्षा हेतु पूर्ण मतोष-प्रद नागरिकता कितनी महत्वपूर्ण है, उसका यह बहुत बड़ा उदाहरण है। यह बात मार्क्स की है कि इस से अनुपातत ब्रिटिश और तुर्की लोगों से अधिक अमेरिकी लोग प्रभावित हुए। कोई भी तुर्की ऐसा नहीं पाया गया, जिसे जरा-सा भी सहयोग देने का दोषी पाया गया हो। इसका कारण अमेरिकी लोगों में अनुशासन की कमी बताया जाता है, जिनमें नैतिकता की भी कमी है।

विभिन्न तरीके

लेखक ने इसे चीनियों द्वारा युद्धबंदियों को शिक्षा देने के लिए प्रयुक्त की गयी तकनीक बताया है। मूलतः इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व को हिंसा, परेशानी, बेइज्जती, बिना नींद लेने का मौका दिये प्रश्न पर प्रश्न पूछ कर, आग्रह, लालच, सजा और इनाम अथवा इन सबके या इनमें से कुछ के उपयोग के जरिये, नष्ट करना शामिल है। मस्तिष्क की वातावरण के साथ अन्योन्यक्रिया व्यक्तित्व है। जब सामान्य वातावरण की जगह असामान्य अवस्थाएँ पैदा कर दी जाती हैं तो व्यक्तित्व में भी परिवर्तन हो जाता है। डा० लिफ्टन कहते हैं— “व्यक्ति के मनोभावों में वातावरण की मनोवैज्ञानिक शक्तियों का प्रवेशन सम्भवतः विचार-संशोधन का प्रमुख मन-श्चिकित्सीय तथ्य है।” अनमनीय वातावरण बना कर व्यक्तित्व को भंग किया जाता है तथा स्वीकारोक्ति निकलवा ली जाती है। इस नये तरीके में कुछ भी नया नहीं है, हाँ, दबाव कुटिल जरूर है। ब्राउन कहते हैं, “इतिहास के आरम्भ से आज तक कोई भी समय ऐसा

नहीं था जबकि पूर्ण अधिकार शक्ति मिलने तथा नैतिकता की कमी होने पर अधिकांश लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी तथा धर्म के समर्थन या विपक्ष में स्वीकारोक्ति करवा लेना सम्भव नहीं था और वह भी सबसे सरल और पुराने तरीके से, न ही कोई ऐसा समय था और न आने वाला है जबकि दृढ़ अल्पसंख्यक अतः तक विरोध नहीं करते रहेगे।” (पृष्ठ २८५) फिर भी स्थायी परिवर्तन तो वातावरण में स्थायी परिवर्तन लाकर ही किया जा सकता है, जिसके लिए ‘दिग्भ्रान्त करने’ की तकनीक पर्याप्त नहीं है। बहुत-से अमेरिकी सैनिकों के मामले में यह पाया गया कि जब वे अपने स्वदेश अमेरिका लौटे तो युद्ध-बंदी शिविर में उन्हें जो शिक्षा दी गयी थी, वह बेकार हो गयी अर्थात् उसे उन्होंने भुला दिया, उसके प्रभाव से मुक्त हो गये। साम्यवादी देश में ‘दिग्भ्रान्त’ अमेरिकी अपने नये विचारों के साथ सुखपूर्वक रह सकता है। परन्तु एक साम्यवादी समाज में वहाँ का वातावरण ही इस तरह के परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित करेगा और ‘दिग्भ्रान्त करने’ की सम्पूर्ण प्रक्रिया बेकार लगने लगेगी। जो लोग साम्यवादी वातावरण के लायक अपने को नहीं बना सकेगे, नये विचार का उनके लिए कोई विशेष मूल्य नहीं होगा और न ही उन पर ‘दिग्भ्रान्त करने’ की प्रक्रिया कोई प्रभाव डालेगी।

व्यावसायिक प्रचार

आम धारणा यह है कि बिक्री विकास के लिए विज्ञापन का माध्यम एक बहुत बड़ा वरदान है। यह इस हद तक सही है कि विज्ञापन के जरिये लोगों तक उनकी जरूरत के भाल अथवा सेवाओं की सूचना पहुँच जाती है। विज्ञापन रुख नहीं बदल सकता, यद्यपि यह रुख की गति को तेज अथवा कम कर सकता है। ब्राउन कहते हैं— “स्थापित रुखों को अच्छे या बुरे के लिए परिवर्तित करने में विज्ञापनकर्त्ताओं अथवा प्रचारकों की तुलनात्मक अस-हायवस्था का प्रमाण इस तथ्य से मिल जाता है कि इस बात का भय पैदा होने पर भी कि सिगरेट पीने से कैंसर

हो जाता है, अमेरिका में १९५० से अब तक सिगरेट की खपत २६ प्रति शत बढ़ गयी है। इसके विपरीत पाइप के तम्बाकू की खपत, बीयर की तरह, धीरे धीरे कम होती हुई १९२० के २१ करोड़ पौण्ड से १९६१ में ७ करोड़ ५० लाख पौण्ड हो गयी है। पहले मामले में स्वास्थ्य प्रचार का तथा दूसरे में विज्ञापनकर्त्ताओं के प्रयास का थोड़ा-सा भी प्रभाव नहीं पड़ा।” (पृष्ठ १८९)

अमेरिका में विज्ञापन-कार्य करनेवाली संस्थाएँ जनता की रुचि तथा भाग की जानकारी के लिए वैज्ञानिकों और मनश्चिकित्सकों को नियुक्त करती हैं। परन्तु विज्ञापन का तरीका वैज्ञानिक नहीं है और सत्य से बहुत दूर है। ब्राउन लिखते हैं— “अधिकांश विज्ञापन, यदि पूर्ण असत्य नहीं है तो, गलत धारणा निर्मित करने के लिए बनाये गये हैं। वैज्ञानिक अथवा दूषित होने के इनके दावे की भी पोल खोल दी गयी है और अधिकांश विज्ञापन तो उचित शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए अपकर्षक हैं।” (पृष्ठ १९१)

प्रचार और जन-संस्कृति

प्रबन्धकीय योग्यता जाचने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की प्रयुक्ति वैज्ञानिक तरीकों को बिल्कुल अवैज्ञानिक अभिप्रायो में प्रयुक्त करना है और सम्बन्धित लोग इस बात को अधिकाधिक महसूस करते जा रहे हैं कि सर्वोत्तम प्रबन्धक उनके द्वारा उपलब्ध नहीं किये जाते जोकि अनुयायी हैं, बल्कि उनके द्वारा उपलब्ध किये जाते हैं जोकि समझ-बूझ के साथ अपने काम को अजाम देते हैं।

चन्द लोगो का कहना है कि जन-सम्पर्क साधन के विकास ने जन-संस्कृति को निराधार कर दिया है। इससे अधिक भ्रामक कुछ नहीं हो सकता। सच तो यह है कि समाचार-पत्र, रेडियो, टेलिविजन और सस्ती पुस्तको जैसे आधुनिक जन-सम्पर्क माध्यमों के विकास के बाद ही आम जनता संस्कृति का फल चखने की अवस्था में आयी है। चूँकि अधिकांश लोग अभी कला और संस्कृति

के सर्वोत्तम नमूनों का रसास्वादन करने योग्य विकसित नहीं हुए हैं, उनके समझने योग्य जो मानक हैं वह उन लोगो को घटिया लगता है जिन्हें कई पुरतों से कला और संस्कृति के फल का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त है। फिर, ये माध्यम सिर्फ सन्ता मनोरजन ही नहीं देते, वे स्तरीय मनोरजन भी प्रदान करते हैं। हो सकता है कि जनता सस्ते किस्म का मनोरजन ही पसन्द करे। जैसा कि लेखक कहता है— “जन-माध्यम के प्रभाव से जो लोग असवेदनशील हो जाते हैं, वे उत्पादक के नहीं बल्कि निष्क्रिय कार्य के शिकार हैं और जो बच्चे भयप्रद फिल्मों, नाटको अथवा पुस्तको की ओर उद्भ्रात रूप में आकर्षित होते हैं वे सामान्य नहीं बल्कि निराश और मनस्तापी हैं।” (पृष्ठ ३१३)

फिर भी, जो मनोरजन प्रदान किया जाता है वह प्रायः उससे अधिक अच्छा है जोकि सामान्यतया जनता चाहती है। फिर, आम दर्शकों की रुचि भी बदलती जा रही है और वे अच्छी चीजों की भाग करने लग गये हैं। निस्सन्देह माध्यम को बदलती रुचि का ध्यान रखना ही होगा। प्रेस, रेडियो और टेलिविजन के लिए अच्छे नियंत्रक सुनिश्चित करने हेतु इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है कि जनता ही अच्छे की भाग करे। जनता को जीवन के सही मूल्यों को समझाने में शिक्षा से बहुत मदद मिल सकती है। ब्राउन लिखते हैं “यह बिल्कुल सही है कि बड़े पैमाने के उत्पादन तरीको पर आधारित समाज ने चुनाव स्वतंत्रता को कुछ लोगो के चुनाव तक ही सीमित कर दिया है, परन्तु इनके साथ ही होनेवाली आर्थिक और शैक्षणिक क्रातियों ने अधिक लोगो के लिए चुनाव की इतनी स्वतंत्रता दे दी है जितनी कि पहले मानव-इतिहास में कभी नहीं थी।” (पृष्ठ ३१७-३१८)

जन-शिक्षा और समाज-सुधार

ब्राउन कहते हैं कि समकालीन प्रचार के अध्ययन से मुख्य पाठ यही मिलता है कि “लोग अपने मन की तसवीर और अपनी वस्तुपरक परिस्थितियों के प्रतिकूल सदेशों

को न मानने के कितने भी विरोधी क्यों न हों, किसी प्रकार वे जान-बूझ कर (भले ही अचेतन रूप में) उन्हीं विचारों को चुन लेते हैं जोकि उनके विचारों से मेल खाते हैं।" (पृष्ठ ३०९, शब्दों का रेखांकन हमारी ओर से) इस प्रकार बच्चों के दो भिन्न दिलों पर एक ही भयप्रद हास्य पढ़ने का दो तरह का असर पड़ सकता है. एक उन्हें एक बार पढ़ कर दुबारा कभी छुएगा भी नहीं, जबकि दूसरा उससे बहुत आनन्द उठा सकता है। वरणक्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि लोग इतने प्रचार के बाद भी उन्हीं चीजों को स्वीकार करते हैं जोकि उन्हें पसन्द है तो प्रचार पर किया जानेवाला खर्च एकदम निरर्थक हो जाता है। परन्तु यह इतनी जल्दबाजी का निष्कर्ष है कि इसकी सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आखिर अगर प्रचार का कोई लाभ होता ही नहीं तो ससार भर के बुद्धिमान लोग इस पर इतना अधिक जो खर्च करते हैं, वे नहीं करते। यह सही है कि प्रचार बुनि-

यादी विशेषताओं को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, परन्तु अवाञ्छित प्रचार मनुष्य की उपचेतन (गैर-समाजी) इच्छाओं को जागृत और तेज कर उसके अवाञ्छित पहलुओं को सामने ला सकता है। जिस हृद तक सामाजिक प्रगति और विकास मनुष्य के स्वस्थ लक्षणों के सामने आने पर निर्भर है, उस हृद तक उसकी राह में आनेवाली बाधा को रोकना ही होगा। यह कहना सहज है, पर करना कठिन है। एक बात स्पष्ट है। यदि स्वस्थ नागरिकता बनानी है तो जन-शिक्षा पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और, बचपन की शिक्षा पर तो विशेष रूप से, जबकि करीब-करीब जीवन-भर के लिए आदत और प्रवृत्ति बन जाती है। परन्तु जब तक अधिकांश लोगों के रहन-सहन की अवस्था तथा जिस वातावरण में उन्हें रहना है उसे, सुधारने के उपाय नहीं किये जाते, सिर्फ शिक्षा से ही कोई खास लाभ नहीं होगा।

बम्बई १६ जून १९६४

श्रीवादी ब्रामोद्योग का एकादश वर्षारम्भ अक सितम्बर के अन्त में प्रकाशित होगा। लेखकों से अनुरोध है कि वे अपने लेख सम्पादक के पास अगस्त १९६४ के प्रथम सप्ताह तक भेज दें।

सहकार पर वैकुण्ठभाई के विचार

रतिलाल मेहता

युग के आरम्भ से ही मनुष्य की गतिविधियों का आधार रहा है सहकार, क्योंकि बिना सहकार के मनुष्य का अस्तित्व नहीं रह सकता। मानवीय इतिहास और सभ्यता में अनेको बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उलट-पुलट हो जाने पर भी सभी देशों में और सब समय, छोटे या बड़े रूप में, उसके प्रमाण मिले ही हैं।

तथापि, पहले के जमाने में सहकारी-जीवन बिताने का प्रयास बहुत-कुछ ढीला-ढाला और असंगठित तथा लोगों के छोटे-छोटे दलों तक ही सीमित था। परन्तु सुस्पष्ट नियमो-विनियमों के साथ संगठित रूप में सहकार का आरम्भ चन्द यूरोपीय देशों में १९वीं शताब्दी के मध्य में आरम्भ हुआ लगता है। उन देशों में मानवीय प्रयास के इस रूप की प्रगति तथा ससार के अन्य भागों में इसके विस्तार का अध्ययन बड़ा ही रोचक और लाभदायक अनुभव होगा।

उद्गम

आज जिसे हम सहकार आन्दोलन कहते हैं उसका जन्म सन् १८४४ में ब्रिटेन के रोचडेल नामक गाँव में तब हुआ जबकि वहाँ के बुनकरों के एक दल ने यह निर्णय किया कि अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति वे स्वयं द्वारा संचालित उपभोक्ता मण्डल की स्थापना कर करेंगे। उसी समय जर्मनी में शुल्क ने कारीगरों और छोटे-मोटे व्यापारियों और रायफेसन ने कृषकों की पृजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई ऋणदात्री सहकारी समितियों की स्थापना की। इन समितियों के संचालन के मुख्य उद्देश्य थे सभी सदस्यों

को समान भताधिकार, प्रबन्ध समितियों के सदस्यों द्वारा मानद सेवा, लघु क्षेत्रों तक काम सीमित रखना ताकि सदस्य एक-दूसरे से सम्पर्क बनाये रख सकें, व्यक्ति के सम्मान को सम्पत्ति से अधिक महत्व प्रदान करना, उचित मूल्य पर बिक्री, खरीदी के अनुपात में लाभ वितरण आदि। लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित इन संस्थाओं में व्यक्ति के हित को सामूहिक कल्याण के अधीन कर दिया गया और उसके जरिये समाज के कमजोर वर्गों को स्वाभाविक संरक्षण प्रदान किया गया। उपभोक्ता और ऋणदात्री समितियों के रूप में आरम्भ हुआ सहकार आन्दोलन तब से अनेक देशों में और मानवीय क्रियशीलताओं के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया है, परन्तु ऊपर जो मूलभूत सिद्धान्त बताये गये हैं, वे ही आज भी आधार बने हुए हैं।

भारत में

इन विचारों की पुष्टि और भारत में इनका इस तरह प्रयोग कि ये इसकी प्रतिभा और इसके सामाजिक पुनर्संगठन की अनिवार्यताओं के उपयुक्त हो— यही खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य श्री वैकुण्ठ ल मेहता के अध्ययन का मुख्य विषय रहा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग लगा दिया है और इस विषय के वे अधिकृत ज्ञाता माने जाते हैं। यद्यपि इस देश में सहकारी आन्दोलन के विकास में उन्होंने मुख्य भाग लिया है और आजादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तथा स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों की रचना में उनसे काफी सहायता प्राप्त की है, तथापि भारत में सहकार के विकास

पर उनके अध्ययन और विचार अब तक विभिन्न पत्रिकाओं, प्रतिवेदनो और पत्रों के पृष्ठों में बिखरे हुए हैं। अतः अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ द्वारा इस विषय पर श्री मेहता के चन्द लेखों, जिनमें से कुछ मूलतः खादी ग्रामोद्योग में प्रकाशित हो चुके थे, का संग्रह (गुजराती अनुवाद)* पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने में पहल करना बहुत ही प्रशंसनीय है। श्रीमती सरलाबेन वी. शाह ने लेखों का बड़ा ही सुन्दर अनुवाद किया है। पुस्तक की भूमिका में श्री विमल शाह ने सहकार आन्दोलन के विकास का संक्षिप्त विवरण तथा सहकार के विभिन्न पहलुओं पर श्री मेहता के विचारों और पर्यवेक्षणों का सार प्रस्तुत किया है।

पुस्तक में १६ अध्याय हैं। आधुनिक भारत में सहकारी आन्दोलन, सहकारी समाजवादी कामनवेल्थ की ओर, समाजवादी नमूने की समाज रचना का मार्ग, मानवीय सुख के लिए अर्थशास्त्र, नया ग्राम समाज, ग्रामीण साख इकाई, कृषि के विकास में ऋण पद्धति की भूमिका, कृषिक ऋण और बिक्री में समन्वय, सहकारी संगठन का स्वरूप, सहकारी कृषि का आधार, सहकारी खेती की आवश्यकता, सहकारी कृषि की उपयोगिता, औद्योगिक विकास और सहकार, औद्योगिक लोकतंत्र की समस्याएँ, सरकारी और गैर-सरकारी सहकारी समितियाँ तथा आदिवासियों में सहकार।

विस्तृत चित्र

यद्यपि ये लेख भिन्न-भिन्न समय में और विभिन्न अवसरों पर लिखे गये हैं और इस प्रकार समय-समय पर उठी समस्याओं पर विचार प्रकट करते हैं, तथापि ये पिछले कुछ दशकों में पश्चिम में सहकार के विकास और भारतीय अवस्थाओं में उनके प्रयोग पर समाग और विस्तृत

* सहकारी समाज वैकुण्ठ ल. मेहता, अंग्रेजी से गुजराती अनुवाद सरलाबेन वी. शाह, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-१४, अप्रैल १९६४, पृष्ठ ११४; मूल्य १.७५ रु., नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-१४ में प्राप्य।

चित्र प्रस्तुत करते हैं। श्री मेहता अपनी सरल परन्तु मेधावी शैली में भारतीय जीवन और अवस्थाओं में सहकार के कार्यान्वय से उत्पन्न होनेवाली विभिन्न समस्याओं पर विचार प्रकट करते हैं और उन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं जो कि उनके गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन, स्पष्ट विचार और यथार्थतम भाव दर्शाते हैं। इन सभी लेखों में मानवीयता की झलक मिलती है। श्री मेहता ने बाम्बे सेट्रल (प्रोविन्सियल) कोऑपरेटिव बैंक लि० (जो कि अब महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० है) के मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, भूतपूर्व बम्बई राज्य के वित्त, सहकार और ग्रामोद्योग मंत्री, अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल तथा उसके उत्तराधिकारी खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष तथा सहकार, वित्त, बैंकिंग, कराधान, प्रशासन आदि विषयक कई जाच समितियों में अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में काम किया है, जिससे उन्हें पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव है तथा देश-विदेश की सहकारी गतिविधियों का अध्ययन तो करते ही रहते हैं, अतः जिन विषयों पर वे विचार प्रकट करते हैं, उनमें उनके ज्ञान और अनुभव का मण्डार फूट-फूट पड़ता है। उनके विश्लेषण और तर्क तथ्यपूर्ण आकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित होने के कारण स्पष्ट और यथार्थ निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। सहकार पर उनके लेख, इस संग्रह के, देश के विकेंद्रित आर्थिक विकास के व्यापक दृष्टिकोण से, जिसके कि इन वर्षों में वे उत्कट और बुद्धिवादी व्याख्याता रहे हैं, समस्या को प्रस्तुत करते हैं।

समाजवाद का मार्ग

पुस्तक के प्रथम पाँच अध्यायों में मुख्यतः सहकार, गणतन्त्र, अर्थशास्त्र, आयोजन, समाजवाद आदि के सिद्धान्तों पर चर्चा की गयी है, जिन्हें कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, विशेष कर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, के पुनर्निर्माण को निर्देशित करना चाहिये। शेष अध्याय कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में सहकार को प्रयुक्त करने के

सम्बन्ध में उनके विचार प्रस्तुत करते हैं।

हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य, जैसा कि वे बताते हैं (पृष्ठ १०), १९४८ में ही श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा (कांग्रेस-अध्यक्ष को प्रस्तुत अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की आर्थिक कार्यक्रम समिति के प्रतिवेदन में) निश्चित कर दिये गये थे। वे थे “हमारा यह उद्देश्य होना चाहिये कि हम एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली विकसित करें, जो शासन-व्यवस्था में निपुणता प्राप्त करते हुए भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उसके साथ संयुक्त करें और साथ ही एक ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार करें, जिसमें व्यक्तिगत एकाधिकार और सम्पत्ति जमा करने की गुंजाइश न होकर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, तथा जिसके द्वारा ग्रामीण और नागरिक अर्थ-व्यवस्थाओं के बीच समुचित सतुलन तैयार किया जा सके। इस तरह का सामाजिक ढांचा व्यक्तिगत पूंजीवाद के धन जमा करने मात्र की अर्थ-व्यवस्था के बदले बनाया जा सकेगा और एकसत्तावादी राज्यों की गुटबन्दी को भी बन्द किया जा सकेगा।” बाद में इन बुनियादी सिद्धान्तों को हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में पावन स्थान दिया गया और इन्होंने तब से पंच वर्षीय योजनाओं की रचना में निर्देश दिया है और उसकी परिणति हुई है

सहकारी, लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिए कार्य करने के निर्णय में। सहकार की समस्या को सुलझाने में श्री मेहता का रास्ता न तो सिद्धान्तवादी है और न ही भावनात्मक, यह तर्क-संगत मार्ग है। भारत के लोकतांत्रिक आर्थिक विकास के लिए सहकार को आधार बनाने का उनका जोरदार आग्रह और दरिद्रनारायण के प्रति उनकी चिंता न सिर्फ गहन अध्ययन का परिणाम है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विशाल जनसमुदाय की नजरों देखी अवस्था का भी।

अतः यह पुस्तक गुजराती साहित्य के भण्डार में तो बुद्धि करेगी ही, अन्य भाषाओं के उद्यमी प्रकाशकों को भी प्रेरणा प्रदान करेगी।

अतः सहकार पर श्री मेहता के लेखों का संग्रह प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक को बधाई। परन्तु एक बात का संकेत न करना अपने कर्तव्य से पीछे हटना है और वह यह है कि यदि लेखों के साथ उनके लिखे जाने की तारीख तथा जिन स्रोतों से उन्हें उद्धृत किया गया है उनके नाम लेख के अन्त में प्रकाशित किये जाते तो, प्रकाशन का महत्व और बढ़ जाता।

बम्बई २१ जून १९६४।

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और प्रामोद्योग कमीशन के लिए ‘प्रामोद्योग’ इलर्ग रोड, विल्हे पार्से (पश्चिम), बम्बई-५९ से प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल एमोसिण्टेड एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ५०५ तारदेव, आर्थर रोड, बम्बई-३४। वार्षिक कुल २ ५० रुपये, एक प्रति २५ पैसे।

दशम वर्ष • अगस्त १९६४ • एकादश अंक



	पृष्ठ
ग्राम्य विकास	-उत्तरंगराय न. देबर ७११
आर्थिक विकास पर प्रधान मंत्री के विचार	-वैकुण्ठ ल. मेहता ७१९
गोबर गैस सयत्र विभिन्न उपयोग और समाज पर प्रभाव	-जशभाई झ. पटेल ७२२
किसानों के लिए उर्वरक	-मगुदेशन बालमुब्रह्मण्यन ७२४
उन्नत धान-कुटाई चक्की	-रा कृ. श्रीवास्तव, एस वाय. नन्दनवार और भा य. राव ७२६
अहमदनगर जिले में गाँवों का आर्थिक सर्वेक्षण और आयोजन	-मधुसूदन द. साठे ७२७
ग्राम्य उद्योगों के विकास के लिए आयोजन	-मरियप्पन प गुरुशामी ७३७
मुंशिदाबाद का सूती और रेशमी खादी उद्योग	-कमल बनर्जी ७४२
वस्त्र छपाई	-दत्तकुमार पै ७४६
औद्योगिक सहकारिताएँ और लोकतांत्रिक समाजवाद	-त्रिलोक नाथ भास्कर ७४८
ग्रामीण औद्योगीकरण और भूमि-सुधार	वे आ. वासुदेवराऊ ७५२
विचार-विमर्श	
लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों का सामान्य प्रबंध	-पे. बाल कृष्ण मूर्ति ७५६
खादी और औद्योगिक कानून	-छीतरमल गोयल ७५८
कृषि में निम्बौरी के गूदे और खली का उपयोग	-अपर्णा सजीव सिक्कर ७६०
भारतीय निर्यात व्यापार तीव्र विस्तार की आवश्यकता	-युवेश चन्द्र शर्मा ७६२
पुस्तक समीक्षा	७६६

स्टडीज इन इण्डियन फॉकलोर शंकर सेन गुप्त और के डी उपाध्याय द्वारा सम्पादित।

दि प्रोमोशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिआज इन इण्डिया इण्टरनेशनल लेबर ऑफिस, नयी दिल्ली।

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोदय', इर्ला, बम्बई-५५ से मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थशास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के क्षेत्र से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ (ए एस) के पते पर भेजें। टेलीफोन नं. ५७१५२९।

स पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिये असिस्टेण्ट एकाउण्ट्स ऑफिसर (केश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ (ए एस)

इस अंक के लेखक

उछरगाराय नवलशंकर देबर

बंकुण्ठ लल्लूभाई मेहता

जशभाई झवेरभाई पटेल

मगुदेसन बालमुब्रह्मण्यन

राम कृष्ण श्रीवास्तव

एस घाय. नन्दवार

भास्कर यशवत राव

मधुसूदन दत्तात्रेय साठे

मरियप्पन पय्यपट्टी गुरुसामी

कमल बनर्जी

दत्तकुमार पै

त्रिलोक नाथ भास्कर

वेदंकरनपुडूर आरुमुगम्
वासुदेवराजू

पेकनाला बाल कृष्ण मूर्ति

छीतरमल गोयल

अपर्णा सजीव सिरूर

युवेश चन्द्र शर्मा

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष ।

—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में गोबर गैस योजना के निर्देशक ।

—अन्नमल विश्वविद्यालय (मद्रास) में अर्थशास्त्र के रीडर ।

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला में प्रभार (सीनियर) वैज्ञानिक अधिकारी ।

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला के भूतपूर्व प्राविधिक सहायक ।

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला में रासायनिक प्रौद्योगिकी सहायक ।

—अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित अहमदनगर जिला सर्वोदय योजना में माख्यकीय सहायक ।

—विस्तार अधिकारियों (उद्योग) के लिए गांधीनिकेतन (टी कल्लूपट्टी—मद्रास) स्थित खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में रेक्टर ।

—बगरा (पश्चिम बंगाल) से प्रकाशित **मुंशिदाबाद समाचार** के सम्पादक ।

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के उत्पादन अनुभाग में चित्रकार ।

—दिल्ली स्थित 'कैपिटल इण्डस्ट्रीज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड' के अध्यक्ष ।

—गांधीनिकेतन (टी कल्लूपट्टी—मद्रास) स्थित विस्तार अधिकारियों (उद्योग) के लिए खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में लेक्चरर ।

—बिडलापुर (चौबीस परगना—पश्चिम बंगाल) स्थित 'बिडला जूट मैन्यू-फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड' में सहायक श्रमिक कल्याण अधिकारी ।

—चौमू (राजस्थान) स्थित राजस्थान खादी सघ के मंत्री ।

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अखाद्य तेल और साबुन उद्योग अनुभाग में प्रचार सहायक ।

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में उप प्रशिक्षण निर्देशक ।

ग्राम्य विकास

उछरंगराय न. देबर

ग्राम्य विकास न केवल ग्रामीणों की भलाई के लिए वरन् राष्ट्रीय समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पिछले वर्षों में कृषिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच निकट सम्बन्ध देखने में आया है। इस निकट सम्बन्ध का एक निहितार्थ यह है कि विदेशी वित्तिय पर बिना अनावश्यक रूप से निर्भर करने हुए ग्राम्य विकास कार्यक्रम के जरिये देश के आर्थिक विकास को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। ग्राम्य विकास को आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम समझा जाना चाहिये। राष्ट्र के दूरदर्शी नेताओं को चाहिये कि वे उमका कार्यान्वयन अपने हाथ में लें।

भारत की राजनीति में जब से महात्मा गांधी ने कदम रखा तब से प्रायः हम एक ही स्वर में ग्राम्य विकास का राग अलापते रहे हैं। यहाँ तक कि गांधीजी के प्रादुर्भाव से पहले भी दादाभाई नवरोजी जैसे व्यक्तियों ने पीडित ग्रामीणों के दुख-दर्दों पर प्रकाश डाला। लेकिन समग्र रूप से देखने पर शहरी नेताओं का रख सहानुभूति दिखाने का ही था। गांधीजी ने इस समस्या को अपने ही ढंग से सबके सामने रखा और केवल उसके बाद ही इस पर कुछ गंभीर रूप से ध्यान दिया गया। जिस किसी ने भी इस प्रश्न के प्रति गांधीजी के दृष्टिकोण का किसी हद तक निरपेक्ष दृष्टि से अध्ययन किया है, वह पहले के राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण की यथेष्टता व सगति पर आपत्ति उठायेगा। प्रारम्भिक दृष्टिकोण में भारत के दुख-दर्दों के मूल और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के अनुरूप एक मात्र प्राणधान समाधान के सम्बन्ध में, यदि अति सामान्यता नहीं तो, महान अनभिज्ञता प्रदर्शित की है। तथापि, अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि समस्या को यथेष्ट रूप में समझा गया है। तथाकथित 'धनिक-शिक्षित-शहरी-बड़ा-भाई' ग्रामीणों पर यदा-कदा जो इस रूप में दया-दृष्टि फेकता है, मानो कि वह गाँवों में रहनेवाले 'गरीब सम्बन्धियों' की दुर्दशा दूर करने की स्थिति में है और वैसा करने का इरादा रखता है, वह इस बात का प्रतिनिधित्व करनेवाली गायद ही समझी जा सके कि शहरी श्रेष्ठी वर्ग ग्रामीण समस्या को उपयुक्त रूप से समझता है। राजनीतिक व समाज-शास्त्र सम्बन्धी बड़ी-बड़ी बातें करने के बावजूद वे

सामाजिक गत्यात्मक नियम संचालन की अनभिज्ञता के ही अधिक द्योतक है।

सामाजार्थिक आधार

गांधीजी राजनीतिक जट्टावली की विशेष चिन्ता नहीं करते थे, लेकिन भारत के विशिष्ट तथ्यों के सम्बन्ध में उनकी जो समझ थी, उसमें किसी प्रकार की भूल नहीं थी— वे सही रूप में भारतीय विशिष्टताओं को समझते थे। उन्होंने यह महसूस किया कि ग्रामीणों का भाग्य शहरी लोगों की दया-दृष्टि पर उतना निर्भर नहीं करना, जितना कि स्वयम् ग्रामीणों की 'अपनी मदद आप करने' की इच्छा और सामर्थ्य पर। भारतीय राजनीति में प्रवेश करते ही गांधीजी ने यह समझ लिया था कि देश की ग्रामीण जनता को बिना फिर से जगाये राजनीतिक क्षेत्र में शहरी बौद्धिक वर्ग चाहे किन्तनी ही बातें क्यों न करे कितने ही भाषण व धमकियों को न दे, मर बेकार जानेवाला है। उन्होंने आधुनिक राजनीति के इस सीधे-सादे सत्य को महसूस कर लिया था कि अन्तर्गत-गत्वा जिम्मा बात का महत्व है, वह है जनता का सामाजार्थिक आधार। भारत का सामाजार्थिक आधार इस बात से निर्धारित होता रहा है और काफी लम्बे समय तक होता रहेगा कि ग्रामीण जनता व ग्रामीण साधन-स्रोतों का क्या होता है। वे कहते थे कि 'भारत गाँवों में रहता है' और फिर आगे कहा करते थे कि 'यदि ग्राम नष्ट होता है, तो भारत का अस्तित्व भी नहीं रह सकता।'।

शहरी में रहनेवाले हम भारतीयों के लिए यह परमा-
वश्यक है कि हम इस बुनियादी सत्य को समझे, महसूस
करें। भारत में प्रगति का मार्ग शहर में नहीं है। वह
गाँव में है और वही रहनेवाला है। तब फिर, ग्राम्य
विकास शहरी धनिकों द्वारा दिया जानेवाला कोई दान
नहीं है। और, न ही वह गरीब ग्रामीण सम्बन्धियों के प्रति
किया गया कोई उपकार है। ग्राम्य विकास भारत के
विकास का अंग्रेसर है—पहले की भाँति आज भी वह इष्ट है।

२

आयोजन और कृषि विभाग

पिछले चौदह वर्ष के दौरान हुए देश के आयोजित
विकास के इतिहास से हमारे सोचने-समझने में यह

महान खामी बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। जहाँ
यह स्वीकार किया जाता है कि आयोजित विकास की
सफलता बहुत कुछ कृषि क्षेत्र में हमारे उद्देश्यों को महसूस
कर लेने पर निर्भर करती है, वहाँ आर्थिक शब्दावली में
इस प्रकार की निर्भरता की सीमा शायद ही महसूस की
जाती है। अब हम उस स्थिति पर पहुँच चुके हैं कि इस
अस्पष्टता के स्थान पर अधिकाधिक स्पष्ट समझ-बूझ
होनी चाहिये। हमें उस क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक वृद्धि
जान लेनी चाहिये जिससे देश की साल दर साल की
स्थायी प्रगति सुनिश्चित होगी। नीचे मैं तीन तालिकाएँ
दे रहा हूँ जो १९४९-५० से १९६१-६२ तक के बारह
वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में हुई वार्षिक कमी-बढ़ती
पर आधारित राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति विशुद्ध उत्पादन

तालिका १

कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धिवाले वर्ष और वार्षिक वृद्धि पर प्रभाव

वर्ष	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन में मूल्य की वृद्धि से वृद्धि	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर १९४८-४९ को आधार मान कर राष्ट्रीय विशुद्ध उत्पादन के पूर्ववर्ती वर्ष के सूच- कांक में वृद्धि	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर १९४८-४९ को आधार मान कर प्रति व्यक्ति विशुद्ध उत्पादन के पूर्ववर्ती वर्ष के सूचकांक में वृद्धि
१९५८-५९	५५० करोड़ रुपये	८ ८	५ १
१९६१-६२	४४० करोड़ रुपये	१० ३	५ ६

तालिका २

कृषि उत्पादन में सन्तोषप्रद अथवा ठीक-ठीक प्रगति और वार्षिक वृद्धि पर उसका प्रभाव

वर्ष	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन में मूल्य की वृद्धि से वृद्धि	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर १९४८-४९ को आधार मान कर राष्ट्रीय विशुद्ध उत्पादन के पूर्ववर्ती वर्ष के सूचकांक में वृद्धि	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर १९४८-४९ को आधार मान कर प्रति व्यक्ति विशुद्ध उत्पादन के पूर्ववर्ती वर्ष के सूचकांक में वृद्धि
१९५२-५३	१६० करोड़ रुपये	४ २	२ १
१९५३-५४	२८० करोड़ रुपये	६ ६	४ ३
१९५६-५७	२३० करोड़ रुपये	६ ०	३ २

तालिका ३

कृषि उत्पादन में न्यून प्रगतिवाले वर्ष और वार्षिक वृद्धि पर प्रभाव

वर्ष	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन में मूल्य की दृष्टि से वृद्धि	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर १९४८-४९ को आधार मान कर राष्ट्रीय विशुद्ध उत्पादन के पूर्ववर्ती वर्ष के सूचकांक में वृद्धि	स्थिर (१९४८-४९) मूल्यों के आधार पर १९४८-४९ को आधार मान कर प्रति व्यक्ति विशुद्ध उत्पादन के पूर्ववर्ती वर्ष के सूचकांक में वृद्धि
१९४९-५०	११० करोड़ रुपये	२ ०	० ४
१९५०-५१	२० करोड़ रुपये (कम)	० ३	-१ २
१९५१-५२	१०० करोड़ रुपये	२ ९	१ १
१९५४-५५	५० करोड़ रुपये	२ ८	० ६
१९५५-५६	१० करोड़ रुपये (कम)	२ ४	
१९५७-५८	२४० करोड़ रुपये (कम)	-१ ३	-३ ३
१९५९-६०	५० करोड़ रुपये (कम)	२ ४	० ३
१९६०-६१	५० करोड़ रुपये (कम)	३ १	०.२

(यह चिन्ह '—' अथवा 'कम' शब्द पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में न्यून उत्पादन दर्शाता है। यही बात राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति विशुद्ध उत्पादन के सम्बन्ध में लागू होती है।)

के सूचकांक में सापेक्षिक वार्षिक घटती-बढ़ती प्रदर्शित करती है। (आधार १९४८-४९ के मूल्यों पर अवलम्बित है।) ये तालिकाएँ देश के आर्थिक विकास और कृषि विभाग की सम्पन्नता का निकट सम्बन्ध बड़े स्पष्ट रूप में सामने लाकर रख देती हैं।

उक्त आंकड़ों के अध्ययन में निम्न निष्कर्ष निकलते हैं

अ कृषि उत्पादन में खूब वृद्धि होने से राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के सूचकांक पर्याप्त रूप से बढ़ जा सकते हैं—तालिका १। (तथापि, आयोजन एक अच्छी फसलवाले वर्ष को अपने कार्यक्रम बनाने के स्तर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता)

आ जैसा कि तालिका ३ में १९४९-५०, १९५१-५२, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५९-६० और १९६०-६१ से संबंधित दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि १ अरब १० करोड़ रुपये तक की वार्षिक वृद्धि से

विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन के सूचकांक में तुच्छ वृद्धि ही हो सकती है।

इ तालिका २ से पता चलता है कि मन्तोषप्रद प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कृषि में स्थिर मूल्यों (१९४८-४९) के आधार पर १ अरब ६० करोड़ से लेकर २ अरब ८० करोड़ रुपये तक की वार्षिक वृद्धि होनी चाहिये। कृषिक उत्पादन में इस क्रम में वृद्धि होने पर ही विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और विशुद्ध प्रति व्यक्ति उत्पादन में क्रमशः चार से छ और दो से चार प्रति शत तक की वृद्धि सुनिश्चित हो सकती है। यह स्वतः स्पष्ट है कि चौदह वर्षों में केवल पांच बार ही हम इन आंकड़ों तक पहुँच सके हैं। मौसम की दृष्टि से दो वर्ष बहुत ही अच्छे रहे। शेष तीन वर्षों में कृषि उत्पादन में औसतन २ अरब २३ करोड़ रुपये वार्षिक के बराबर वृद्धि हुई। अगर हम राष्ट्रीय उत्पादन में पांच अथवा

प्रति व्यक्ति उत्पादन में दो से चार प्रति शत तक की वृद्धि का भी लक्ष्य सामने रखे तो भी हमें इस आधार पर आयोजन करना होगा कि कृषि उत्पादन में २ अरब ३० करोड़ रुपये के बराबर वृद्धि सुनिश्चित हो। मेरा विचार है कि यह पांच प्रति शत वृद्धि दर, विकास की बात तो अलग छोड़िये, निचले स्तरों पर आर्थिक पुनर्स्थापना की गम्भीर समस्या को मुलज्जाने तक के लिए परिपूर्ण अपर्याप्त है। अमल में राष्ट्रीय आय में मात्र प्रति शत वार्षिक के लगभग वृद्धि का होना आवश्यक है। इस हिसाब से कृषि उत्पादन में वृद्धि और भी अधिक होनी चाहिये— वर्ष १९४८-४९ में प्रचलित मूल्यों की शब्दावली में कृषि विभाग में यह वृद्धि तीन अरब रुपये वार्षिक अथवा उसके लगभग होनी चाहिये।

प्रतिकूल मौसम के लिए प्रावधान

यदि हम चाहते हैं कि हमारा विकास का स्वप्न आज की तरह मात्र कागजी परियोजना न बनी रहे तो फिर हमारे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमें कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इस प्रकार का आयोजन करना पड़ेगा कि १९४८-४९ के मूल्यों के अनुसार तीन अरब रुपये वार्षिक के बराबर वृद्धि हो। कृषिक आयोजन में मौसम आदि जैसे कारकों का निश्चय ही सम्बन्ध है अर्थात् उन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन चूँकि वे सगत हैं, इसलिए उनका ध्यान उक्त क्रम में वृद्धि करने की दृष्टि से रखा जाना चाहिये न कि कमी की अवस्था में औचित्य प्रदान करने के लिए। इसका मतलब है कि प्रकृति के साथ मुकाबला एक ऐसा कारक है जिसके लिए स्पष्ट रूपेण योजना बनानी पड़ेगी, ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण हमारा आयोजन ही खनरे में न पड़ जाय।

उक्त नालिकाओं में विकास की अहिम्न प्रक्रिया का भी पता चलता है। वे इस दलील का खण्डन करती हैं कि विज्ञान, रंग और विदेशी विनियम विषयक आवश्यकताओं में सहज सम्बन्ध है और उनसे यह बात

भी सामने आती है कि जो उत्पादन वृद्धि करनी है उसमें समय की दृष्टि से विलम्ब नहीं होना चाहिये। सीमित विनियम आवश्यकताओं तथा सापेक्षिक दृष्टि में कम पूँजी के साथ उत्पादन की शब्दावली में तुरन्त फल-प्राप्ति करना और इस प्रकार कमी तथा स्फीति के दुष्चक्र को भी तोड़ना सम्भव हो सकता है।

३

ग्राम्य क्षेत्रों की अवहेलना

इस प्रकार हमारा विकास कार्य ग्राम्य क्षेत्रों पर कितना अधिक निर्भर है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके सबब में शहरी बुद्धिजीवी वर्ग का ज्ञान धूमिल-सा ही है। इन परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान करने का दिखावा करना मात्र कपट भ्रमता है। कुल मिला कर देखने पर भारतीय समस्याओं की जटिलताएँ शहरोन्मुख नेतृत्व की इस प्रारम्भिक अज्ञानता के कारण खड़ी होती हैं, जोकि आधुनिकता के प्रति अपनी व्यग्रता के कारण तथ्यों का अनवरत उपहास कर रहा है। हमारी आर्थिक विचारधारा में जो भी विकृतियाँ दिखायी देती हैं, उनका उद्गम इसी शहरोन्मुख दृष्टिकोण में है, जोकि आज भी हमारा पथ निर्देश करता है और हमारी विचारधारा पर भूत की तरह सवार है।

भारतीय संसद के गत शरद-कालीन अधिवेशन में जब पण्डितजी ने यह स्वीकार किया कि वे यह सोचने लगे हैं कि हमें गांधीवादी दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ेगा, तो वे यह चाहते थे कि देहातो की समस्या के समाधान पर ध्यान दिया जाय। लेकिन उनका मतलब यह नहीं था कि उद्योगीकरण के लिए जो बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं, उनका त्याग कर दिया जाय, इसलिए उन्होंने देश के विकास की समस्या के प्रति एक ऐसा नया प्राणवान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया कि उससे ग्राम्य क्षेत्रों में सामाजिक शक्तियों में जान आ जाय, वे सक्रिय हो उठें। इस नव दृष्टिकोण का निहितार्थ

यह है कि यह कृत्रिम विचार अथवा धारणा बिल्कुल भ्रातिमूलक है कि भारत को अमेरिका और रूस का अनुकरण करने की आवश्यकता है, बस, फिर अपन आप उसे नया स्वर्ग मिल जायेगा। हो सकता है कि कुछ को यह सत्य बुरा भी लगे, लेकिन इसका सामना करना ही होगा। भारत ठीक उसी प्रकार अमेरिका अथवा रूस नहीं हो सकता, जिस प्रकार वे भारत नहीं हो सकते। हमारी अपनी पृष्ठभूमि, अपनी समस्याएँ और अपने साधन-स्रोत हैं। ये शक्तिदायक पहलू तभी हो सकते हैं, जबकि हम इनकी कमजोरियों से बचते और मजबूतियों का ध्यान रखते हुए अपनी समृद्धि के लिए आधार बनाने की कोशिश करें। ग्राम्य क्षेत्रों की उनकी पृष्ठभूमि, उनकी समस्याओं और उनके साधन-स्रोतों के साथ अवहेलना करने के लिए अंग्रेजों को अपने साम्राज्य तथा भारतीय जागीरदारों को अपनी जागीरों से हाथ धो बैठने के रूप में मूल्य चुकाना पड़ा है। पिछले पन्द्रह वर्ष के अनुभव से पता चलता है कि इस मूलभूत तथ्य की सापेक्षिक अवहेलना से भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सरदर्द पैदा हो रहा है।

खाद्यान्न आयात के निहितार्थ

अनवरत रूप से चली आ रही हमारी अन्न की कमी इसी वृत्त का एक अंग है। उदाहरण के लिए देश में चावल और गेहूँ की स्थिति को ही ले लीजिये। ग्रामीणों से केवल अपना जरूरत से ज्यादा अनाज ही वेचने की अपेक्षा की जा सकती है। गेहूँ के मामले में किसानों के पास बिज्जी के लायक अतिरिक्त गेहूँ चालीस लाख टन है। इसमें लोगों की केवल आधी आवश्यकता ही पूरी हो सकती है। शेष की पूर्ति आयात करके करनी पड़ती है। आयात का मतलब है पी एल ४८०, पी एल ४८० का अर्थ है अर्थ-व्यवस्था में उतने रूपों का और समावेश, रूपों के समावेश—उत्पादन में उसी के समान वृद्धि किये बिना—के माने हैं स्फीति, स्फीति का तात्पर्य है अव्यवस्था व अशांति। इन परिस्थितियों में यह कहना

ओछापन है कि ग्राम्य विकास ग्रामीण जनता के लिए है। कभी-कभी ग्राम्य विकास ग्रामीणों की अपेक्षा शहरवासियों के लिए अधिक आवश्यक है।

४

ग्राम्य विकास व उद्योगीकरण में विरोध नहीं

ऐसी धारणा पायी जाती है कि ग्राम्य विकास के हिमायती उद्योगीकरण के विरोधी हैं। राष्ट्र के हित में इससे अधिक भ्रामक अथवा अहितकर अन्य कोई बात नहीं हो सकती। ग्राम्य विकास में उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग, सिंचाई योजनाओं के निर्माण की बात शामिल है, जिनके लिए बहुत बड़ी तादाद में सिमेंट व इस्पात तथा अन्य ऐसी ही सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं हमने बिजली के उपयोग तक का सवाल आता है। परिवहन की सुव्यवस्था इसके लिए आवश्यक है। यह मानना कि ये यथार्थ रूप में औद्योगिक परियोजनाएँ नहीं हैं, नाममझी की-सी बात है। क्या कभी किसी ने ऐसा कहा है कि भाखरा-नागल बाध के हजारों हिस्से कर दिये जायें? वस्तु स्थिति यह है कि ईंधन, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली व परिवहन जैसी योजनाओं को सदैव ही पंगिपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। यह सच है कि साथ ही साथ हमने प्रशोधन और उगमोग उद्योग के क्षेत्र में ग्राम्य उद्योगीकरण आवश्यक समझा है। लेकिन ग्राम्य उद्योगीकरण तो ग्राम्य विकास का एक ही अंग है। ग्राम्य विकास का अर्थ कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास ही नहीं है। 'ग्राम्य विकास' शब्द एक बहुत ही व्यापक, प्राणवान शब्द है। देश में एक सच्चे माने में विकासशील प्रयास का आधार ग्राम्य विकास ही बन सकता है। गांधीजी के समय से ही ग्राम्य विकास-पर जो जोर दिया जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि यही है।

मलभन मवाल तो यह है कि कोन-सी विकाम परियोजनाओं को प्रथम स्थान दिया जाय— भारत के विकास के सामाजिक पक्षों से असम्बद्ध 'उद्योगीकरण की परियोजनाओं' को अथवा उन 'उद्योगीकरण की परियोजनाओं' को जो कम से कम सम्भव समय में देश की अर्थ-व्यवस्था

के इस प्राणवान सामाजार्थिक आधार के विकास में योगदान दे सकती है, सहायक हो सकती है। भारत को ग्राम्य और गहरी दोनों क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि गाड़ी को बैलों के जोता जाय या बैलों को गाड़ी के। ग्राम्य विकास पर लगातार जोर देने के पीछे दृष्टिकोण है निरोधित-पूर्वाग्रही शहरोन्मुखी विचारधारा को भारतीय परिस्थिति की वास्तविकताओं का सही रूप में भान करवाना। सामाजिक पुनरुत्थान के नियमों पर आधारित ग्राम्य विकास के चक्र को सन्निवृत्त बनाने के लिए यह एक हेतु है।

ग्राम्य विकास का मतलब उद्योगीकरण से इन्कार नहीं है। इसका अर्थ इस दावे से इन्कार है कि आर्थिक विकास का पाश्चात्य ढंग भारत में भी लागू किया जा सकता है। देश में यथेष्ट रूपेण उद्योगीकरण होगा। तथापि, वह सामाजार्थिक पुनरुत्थान का एक ऐसा दुर्ग होगा, जिसकी नींव ग्राम्य विकास में, गाँवों में होगी। औद्योगिक विस्तार की शब्दावली में प्राथमिकता कृषि-उद्योगों के लिए आवश्यक आर्थिक मदों को (जैसे सड़क, बिजली, इस्पात, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि) निर्मित करने के लिए योजनाओं को मिलनी चाहिये।

५

साधन-स्रोतों का उपयोग

ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे साधन-स्रोतों की भरमार है, जिनका उपयोग और विकास करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन-शक्ति सम्बन्धी हमारे साधन-स्रोतों का अपनी पिछड़ी अवस्था में होते हुए भी राष्ट्रीय उत्पादन में करीब ६० प्रति शत योगदान है। उन्हें उपयुक्त दिशा में प्रवृत्त कर हम उन्हें बेहतर तथा और अधिक फलदायी कामों में लगा सकते हैं। लगभग ६० प्रति शत व्यक्तियों के पास अर्पय्य जमीन है। करीब तीन-चार करोड़ के पास पर्याप्त काम नहीं है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था की बैलगाड़ी पर भार इतना अधिक हो गया है कि

वह क्षत-विक्षत हो जाने की अवस्था पर पहुँच चुकी है। भार के नीचे वह टिडक रही है, लेकिन उसमें एक क्षमता है। कार्य-स्थल पर अवसर उपलब्ध है। काम करने के लिए व्यक्ति मौजूद है। विश्व में पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्य है। प्राविधिक प्रगति की भी कमी नहीं है। वैज्ञानिक तौर-तरीकों और उन्नत साधन-संरजाम का उपयोग कर उसी जमीन से पर्याप्त अधिक उपज हासिल की जा सकती है। इन सब में ३२ करोड़ काम करनेवालों के हाथ लगने से भारत का नाम रोशन हो सकता है, उसका सितारा बुलंद हो सकता है। और, जैसा कि लार्ड वेवल (Lord Wavell) ने कहा है, मन्द गति से चलनेवाली बैलगाड़ी शीघ्र ही जीप का रूप धारण कर सकती है।

न्यून वन्य उत्पादन

भारत में २,३०,७८९ वर्ग मील पर-देश के लगभग एक-पचमाश भौगोलिक क्षेत्र में-जंगल है। इनसे हमें ५५ करोड़ घनफुट इमारती लकड़ी, ईंधन और काठ की प्राप्ति होती है। समार के प्रति वर्ग मील ४,००० घनफुट औसत के समक्ष हमारा औसत २,००० घनफुट प्रति वर्ग मील है। हमारे कुछ वन्य क्षेत्र तो, खास कर विन्ध्य श्रेणी, घाट और हिमालय के वन्य क्षेत्र, विश्व में सर्वोत्तम हो सकते हैं। इटली में हमारे वन्य क्षेत्र के दसवें हिस्से के बराबर इलाका होते हुए भी वह हमसे सवाया पैदा करता है। इसी प्रकार फ्रांस हमारे वन्य क्षेत्र के छठे हिस्से के बराबर क्षेत्र रखते हुए भी हम से ढाई गुना अधिक वन्य उत्पादन करता है। चीन में भारत से १२ प्रति शत ज्यादा क्षेत्र में ही जंगल है, लेकिन उसका कुल वन्य उत्पादन हम से तीन गुना है। भारत के एक-पचमाश क्षेत्र के विपरीत युगोस्लाविया में कुल के ३६ प्रति शत इलाके में जंगल है। इजराइल में यदि तीव्र गति से वृक्षारोपण किया जा सकता है तो वैसे भारत में भी हो सकता है।

हमारे वनों में अन्याय कार्यशीलताओं के विकास की अत्यधिक गुंजाइश है। उदाहरणार्थ जलावन, लकड़ी का कोयला और पत्थर का कोयला (कोक), खाद

समग्रह, गौण उत्पादन तथा जडी-बूटियों का समग्रह, गोद, खालो, पेड़ो के तनो का एकत्रण, उपस्कर बनाना और निर्माण उद्योग का विकास, अखाद्य तिलहन, काठ, बेत, बास और रेशो का समग्रह, कागज उद्योग का विकास, टसर, ऊन और रेशम कीट-पालन का विकास, बाग-वानी, फलोत्पादन और उन्हे डिब्बो में बन्द करने के काम का विकास, दुग्धोद्योग आदि। भारत के जंगलो की क्षमता इतनी अधिक है कि उस पर विश्वास नहीं हो पाता—वह कल्पनातीत है। हमें केवल इसकी ओर अपना ध्यान भर पलटना है। इसके उपयोग के लिए शक्ति-बुद्धिमत्ता और पौरुष की आवश्यकता है— बस, फिर सब कुछ होता चला जायेगा।

पशु-पालन

अब हम देश में पशु-पालन पर भी विचार करें। भारत में किसान और पशु-पालक अपनी २० से ३० प्रति शत तक आय के लिए मवेशियों तथा अन्य पशुओं पर निर्भर करते (जैसा कि विश्व के प्रत्येक देश में उन्हे निर्भर करना पड़ता है) हैं। भारत में पशु-सुरक्षा और पशु-विकास के लिए पंजाब के सिवाय अन्यत्र कहीं कुछ नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण आधिकारिक पदों पर आसीन व्यक्तियों ने तो यही मान लिया है कि भारतीय मवेशी बेकार हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उनकी क्षमता का विकास करने की कोशिश की है? पंजाब में हरियाणा, बीकानेर, जोधपुर, वाडमेर और जैसलमेर के इलाका में थम्पाडकर और राठ, दक्षिण-पूर्व राजस्थान तथा उत्तर-पश्चिम गुजरात में साचोरी और काकरगेज, सौराष्ट्र में गिर, मैसूर में बगलोर, आन्ध्र प्रदेश में ओंगगोल, मध्य प्रदेश में मालवी तथा देश के कुछ अन्य छोटे-बड़े हिस्सों में पायी जानेवाली ऐसी ही नस्लों के पशु बहुत उत्तम कोटि के होते हैं। और, उनकी संख्या एक-दो में नहीं, लाखों में है। यही बात पंजाब की मुर्र और गुजरात की सूरती मैसो के बारे में कही जा सकती है। ज़रूरत है उन पर व्यक्तिगत ध्यान देने और उन्हे अच्छा चारा खिलाने की। व्यक्तिगत ध्यान

तथा पर्याप्त पौष्टिक खुराक की कमी ही एक मात्र कारक है, जो इन नस्लों के विकास में बाधक है।

ग्रामोद्योग

यही हालत दस्तकारियों और ग्राम उद्योगों की है। यह सच है कि दस्तकारियों तथा ग्राम उद्योगों के समर्थकों ने कभी-कभी उनके विकास की समस्या के प्रति पुराना दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन उनके हाथ से इनका विकास कार्य लेकर उममें नवीनतम वैज्ञानिक व प्राविधिक उपकरण एवम् तौर-तरीके लागू करने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता था।

आज भी वैसा कर लेने में कोई देर नहीं हुई है। ग्राम्य विकास से चन्द गांधीवादियों का ही ताल्लुक न समझ कर, यदि मात्र राष्ट्रीय नेतृत्व भी यह समझ ले कि ग्राम विकास ही वह मूलभूत माध्यम है, जो भारतीय आर्थिक विकास में गति पैदा कर सकता है तो वह अब भी स्थिति में सुधार ला सकता है, उस पर काबू पा सकता है।

लेकिन क्या हमें अपनी विचारधारा की इस अपूर्णता और इस नये दृष्टिकोण की शक्यता के बारे में दिलजमई हो चुकी है? क्या हमारा मस्तिष्क इस सबध में बिल्कुल स्पष्ट है कि वास्तविक आर्थिक प्रयास का प्रारम्भ बिन्दु इस उक्त अर्थ में ग्राम्य विकास ही हो सकता है? क्या हम इस सबध में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भारतीय अवस्थाओं में आवश्यक न्यूनतम सात प्रति शत विकास दर इस महत्वपूर्ण विभाग के विकास के जरिये ही सम्भव है? उपर्युक्त ताल्लिकाओं में दिये गये १९५८-५९ और १९६१-६२ के आकड़े हमारे सामने हैं। राष्ट्र केवल कृषि के कारण ही उक्त वर्षों में ८ से १० प्रति शत के बीच विकास दर हासिल कर सका था। योजना में अलग प्रकृति हमें जो दे सकती है, क्या हम उसी योजना नहीं बना सकते?

इसका मतलब है हमारी योजना के प्रति अर्थात् स्वयम् उम्मी में ही एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाना।

इसका अर्थ है विकास की समस्याओं के प्रति एक परिपूर्ण नया दृष्टिकोण अपनाना। इसके माने हैं प्रशामन के क्षेत्र में नये दृष्टिकोण का समावेश। इसका अर्थ है फिलहाल के लिए पाश्चात्य जीवन-पद्धति व कार्य-प्रणाली और उद्योगीकरण के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए जो लोलुपता या उत्सुकता, अथवा और कुछ, है उसका परित्याग।

मैं मानता हूँ कि मार्ग में बाधाएँ अनेक हैं। पिछले पन्द्रह वर्ष की अवधि में हमने अनेक प्रकार के वादे किये हैं। मौजूदा प्राथमिकताओं और उद्योगीकरण के वर्तमान स्वरूपों को आसानी से बदला नहीं जा सकता। तथापि, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि वादों पर पुनर्विचार किया जाय, प्राथमिकताओं को एक-एक करके तब तक ऊपर-नीचे किया जाय जब तक कि वे पुनर्व्यवस्थित न हो जायें और बैल, गाड़ी में उपयुक्त स्थान पर न जुट जाय ? क्या हम कृषि, वन्य-उत्पादन, भूमि-संरक्षण, पशु-पालन, ग्रामीण उद्योगों और इसके लिए आवश्यक उन आर्थिक मदों, जिनका उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों में हो सकता है, में हम ग्राम-जन-प्रयाम की दिशा में अपने को लगाने के लिए तैयार हैं ? तब, हमारे आयोजन

में बिजली, औद्योगिक कच्ची सामग्री तथा अन्य आवश्यकताओं और परिवहन एवम् प्रशिक्षण, अन्वेषण व शैक्षणिक नूतनता के रूप में सुविधाओं को एक युक्ति-संगत स्थान प्राप्त होगा।

हमें कच्ची सामग्री तथा वित्त के वितरण के सवाल को उक्त दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार रहना होगा। तब हमें अपने को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि कच्ची सामग्री के मामले में किमान, पशु-पालक और ग्रामीण कारीगर की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाय। हमें ग्राम्य नूतनता की कसौटी पर भी राजनीतिक तथा प्रशासनात्मक दोनों ही क्षेत्रों में सस्थात्मक स्वरूप का मूल्यांकन करने के लिए भी तैयार रहना होगा। राष्ट्रीय व्यय और राष्ट्रीय जीवन पद्धति के सबंध में हमें अपने विचार को नया रूप देना होगा अर्थात् नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें और भी सैकड़ों काम करने होंगे। लेकिन यदि राष्ट्र को विप्लव और/अथवा साम्यवाद में बचाना है तो ये सब आधारभूत बातें हैं।

बम्बई १४ जुलाई १९६४

नैतिकता के दो पक्षों में एक पक्ष आत्म-संयम का है, अपने आप अपनी प्रेम-भावना और इच्छा-शक्ति पर काबू पाना आत्म-संयम है। बर्थेम ने कही भी इसका जिक्र नहीं किया है। दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है अपने आचरण को नियमित करना। बिना पहले के यह भी अनिश्चित और अपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी अथवा दूसरों की भावना व इच्छाओं को समझ न ले, तब तक यह निर्णय कैसे कर सकते हैं कि हमारी 'करनी' हमारे अथवा दूसरों के सासारिक हितों पर कैसा प्रभाव डालेगी? बर्थेम के सिद्धान्तों के अनुसार नीतिज्ञ इतना कह सकता है कि मनुष्य को हत्या नहीं करनी चाहिये, आग नहीं लगानी चाहिये अथवा चोरी नहीं करनी चाहिये, परन्तु मनुष्य के श्रेष्ठ आचरण के लिए उसका क्या कहना है अथवा चरित्र पर प्रभाव डालनेवाले तथ्यों सम्बन्धी नैतिक मूल्य निश्चित करने के विषय में उसका क्या विचार है, जोकि यौन सम्बन्ध, सामान्य पारिवारिक सम्बन्ध अथवा अन्य किसी निकटवर्ती या सामाजिक सम्बन्ध जैसे भौतिक कारकों की अपेक्षा मानव चरित्र को अधिक प्रभावित करते हैं ?

— बर्थेम पर जॉन स्टुअर्ट मिल

आर्थिक विकास पर प्रधान मंत्री के विचार

वैकुण्ठ ल. मेहता

आनुक्रमिक पंच वर्षीय योजनाओं की परिकल्पनाएँ उत्साहजनक चित्र प्रस्तुत नहीं करती। अतः प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने योजनाओं को नया मोड़ देने तथा उन्हें रोजगार-मुखी बनाने पर जोर दिया है, वह समयानुकूल है।

अव्यय की हैसियत में योजना आयोग की पहली बैठक में प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने भाषण के दौरान जो नया विचार ममाने खा उसके लिए कोई भी उनका कृतज्ञ हुए विना नहीं रह सकता। अब जबकि हमने तीसरी पाँचसाला योजना का मध्य-कालीन मूल्यांकन कर लिया है, और यद्यपि चौथी योजना के सम्भाव्य आकार तथा विषयो की मोटी रूपरेखा भी दी जा चुकी है, फिर भी क्या अभी समय नहीं है कि हम पिछले अनुभवों और वर्तमान अवस्थाओं के आधार पर हमारी योजना में प्राथमिकताओं के क्रम निर्धारण पर पुनर्विचार न करे।

परिकल्पनाएँ निरुत्साहजनक

इसके लिए प्रधान मंत्री के विचारों ने एक मार्ग प्रशस्त किया है। सर्व प्रथम वे यह चाहते हैं कि योजना रोजगार-मुखी हो। “रोजगारी के अवसरों का पर्याप्त विस्तार” निस्सन्देह तीसरी योजना के पाँच मुख्य उद्देश्यों में से एक है। परन्तु अब तक जिम गति और जिम तरीके से आर्थिक विकास हुआ है, उससे यह माना जाता है कि योजना के अन्त में बेकार लोगों की संख्या, उसके प्रारम्भ में जितने बेकार लोग थे, उनसे बहुत अधिक रहेगी। अगर हम इसी तरह बढ़ते रहे तो, हमारी आबादी वृद्धि की गति धीमी होने पर भी, अवस्था हर वर्ष गिरती ही जायेगी। बसका हथारे करोड़ों लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं।

हाल ही में हमारी आगामी योजनाओं की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत की गयी हैं। उनकी सगणना से लगता है कि पंचम पंच वर्षीय योजना के अंत में अर्थात् अब से बारह वर्ष बाद देश में किसी भी व्यक्ति की आय २० रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। इस अनुमान पर तो शका करने का कोई कारण ही नहीं है, परन्तु यह समझना बड़ा कठिन है कि क्या यह सात्वना दे सकता है। यह मान लिया जाय कि १९७६ में रुपये का मूल्य आज के ही समान रहेगा, तो भी २० रुपये प्रति माह आय का अर्थ है ६६ पैसे दैनिक आय, जोकि आज देश के अधिकांश भाग में प्रचलित कृषि-मजदूरी दर की आधी है। वार्षिक आय २४० रुपये होगी, जोकि आज की प्रति व्यक्ति आय की तीन-चौथाई है। यह अक तो विग्व के जिन देशों के साख्यिकी आकड़े उपलब्ध हैं, उनमें सबसे कम है। यदि २५ वर्ष के आयोजन के बाद भी हृष यही प्रगति कर सकते हैं, तो जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि क्या हमारी योजना को नया मोड़ देने का यही समय नहीं है ?

नयी दिशा का संकेत

प्रधान मंत्री ने नयी दिशा का एक संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सिचाई के लिए बड़े-बड़े बाध बाधने हेतु देश के पास पर्याप्त खोत नहीं है तो आयोग को अपभीन नहीं होना चाहिये। तालाबों और कुओं के निर्माण और मरम्मत के लिए जोरदार प्रयास किये जा सकते हैं। ये तथा अन्य लघु सिचाई कार्य रोजगारी के अवसर बढ़ायेगे, उनके लिए यत्र मगाने हेतु विदेशी विनियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये काम

हमारे देश में बहु सख्या में उपलब्ध मिविल-इजीनियर कार्यान्वित कर सकेंगे। हो सकता है कि मिचाई के अन्तर्गत लाये गये खेतों में प्रति एकड़ खर्च बड़ी परि-योजनाओं के खर्च के मुकाबले थोड़ा-सा अधिक हो, लेकिन इसके विपरीत इसका लाभ भी शीघ्र ही मिलेगा और अपने खेतों तथा जंगलों से विस्थापित होनेवाले लोगों की सख्या भी बहुत कम होगी।

खाद के स्रोत

प्रधान मंत्री ने रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धि की भी बात कही। कुछ वर्गों में तो इसे स्वयम् सिद्ध सत्य मानते हैं कि उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए फसलों में रासायनिक खाद डालनी ही होगी। यदि यह देशी स्रोतों अथवा आयात के जरिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती तो हम उत्पादन वृद्धि की आशा नहीं कर सकते। स्वयं में यह स्वयंसिद्ध प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने आग्रह किया कि यदि खाद-स्रोतों की कमी राह में बाधक है तो अन्य खाद-स्रोतों की खोज कर इस बाधा को दूर करना चाहिये। हमारे नियोजित कार्यक्रम के प्रारम्भिक सोपानों में कम्पोस्ट खाद की प्राप्ति और पूर्ति पर बहुत जोर दिया गया था। कार्यक्रम में तो यह अब भी शामिल है, परन्तु इसके लाभों के विस्तार के लिए कोई जोरदार प्रयास किया जा रहा हो, ऐसा सुनने में नहीं आता।

चूँकि गोबर हमारी भूमि और हमारी फसलों की विशेष आवश्यकता-पूर्ति के लिए मूल्यवान खाद प्रदान करता है, अतः यदि इसे सिर्फ खाद के लिए सुरक्षित रखा जाय तो बारिश पर निर्भर करनेवाली फसलों में विशेष कर बहुत वृद्धि होगी। दुर्भाग्यवश अभी भी गोबर की बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग जलावन के रूप में किया जाता है। यदि इसे रोकना है तो देश भर में जलावन के अन्य विकल्पों की योजना होनी चाहिये, जिसमें गोंव के निकट ही शीघ्र बढ़नेवाले वृक्षों का रोपण भी एक हो सकता है।

चीन और जापान, इन दोनों ही देशों में मल-मूत्र का उपयोग फसलों के उर्वरक के रूप में करते हैं। हमारे गाँव में मल-मूत्र की निकासी का जो तरीका है, वह तो सम्पूर्णतया इसे व्यर्थ जाने देने का ही है, शहरों में इसका तरीका गन्दा और अपमानजनक है। जिन चन्द शहरों में स्रोतों को सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ उनकी अच्छी बिक्री हो जाना यही दर्शाता प्रतीत होता है कि मल-मूत्र के उपयोग का विरोध उतना गम्भीर नहीं है, जितना कि उद्यमी किसानों को इसे खाद के रूप में दस्तेमाल करने से रोकना। कुछ हद तक यही बात पशु-शवों के उपयोग के विषय में भी लागू होती है, जोकि विशेष कर गाँवों में तो बर्बाद ही जाते हैं, - - - - - मावित हो सकते हैं।

जन-शक्ति स्रोतों का उपयोग

देश में व्याप्त गरीबी का "देश के जन-शक्ति स्रोतों के पूर्ण उपयोग—" जोकि हमारे आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य है— में हमारी अपेक्षाकृत असाक्षरता के साथ जिक्र करते हुए प्रधान मंत्री ने आवश्यक रूप से मध्यम, लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास पर जोर दिया, क्योंकि उनमें सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों के मुकाबले रोजगारी देने की अधिक क्षमता है। इस प्रकार रोजगारी के प्रसार हेतु विकेन्द्रित आधार पर औद्योगिक उत्पादन अनिवार्य हो जाता है।

प्रशोधन उद्योग का यांत्रिकृत विभाग

ऐसी बात नहीं है कि प्रधान मंत्री ने जिन बातों पर जोर दिया है, उन पर योजना आयोग का ध्यान ही नहीं गया है। जून १९५५ में ही आयोग ने ग्रामीण और लघु उद्योग समिति की नियुक्ति विशेषतया इसलिए की थी कि वह अर्थ-व्यवस्था के इस विभाग के लिए इस उद्देश्य से योजना बनाये कि 'योजनावधि में आम माँग की उपभोक्ता सामग्री के बड़े उत्पादन का अधिकांश भाग ग्रामीण और लघु उद्योग पूरा करे।' इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा एक संयुक्त

उत्पादन कार्यक्रम बनाने की कोशिश की गयी है।

दुर्भाग्यवश पिछले वर्षों में कटाई मिले, शक्ति-कटघे, तेल मिले और चावल मिले खोलने की आज्ञा दी गयी है और चन्द राज्यों में तो वे प्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम के अग स्वरूप पनप रही है। सबसे ताजा उदाहरण तो सरकार के लिए ही विदेशों से आयात किये गये यन्त्रों की मदद से छ आधुनिक चावल मिले खोलने का प्रस्ताव है।

फिलहाल जैसी स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए यदि सम्पूर्ण देश की दृष्टि से देखे तो यात्रीकृत विभाग की क्षमता का एक अंश अनुपयोगित पड़ा है, और हलरो की स्थापना—अधिकृत अथवा अनधिकृत

रूप में—से तो हस्त प्रशोधन उद्योग में भी काफी क्षमता अनुपयोगित पड़ गयी है। इन परिस्थितियों में योजना आयोग को इस सम्बन्ध में विचार करना होगा कि बड़ी क्षमतावाली इन मिलों की स्थापना से हाथ धान कुटाई उद्योग के जरिये दी जानेवाली रोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसके विकास के लिए योजना में शामिल एक कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना बनाने अथवा उपर्युक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के पूर्व योजना आयोग द्वारा इस पर विचार करना वाछनीय होगा कि वे प्रधान मंत्री द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

पूना १७ जुलाई १९६४

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आकड़ों तथा आय कर-दाता वर्ग की आय के आकड़ों का उपयोग करते हुए लीडल ने सम्पूर्ण शहरी और ग्रामीण आबादी तथा दोनों के लिए अलग-अलग भी वर्ष १९५५-५६ के लिए प्रति व्यक्ति मासिक आय के जरिये आय के वितरण का अन्दाज लगाया है। इन आकड़ों के अनुसार ८६ प्रति शत आबादी की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ३६० रुपये में कम और ९६ प्रति शत की २४० रुपये से कम है। यह मान कर कि २४० रुपये और ३६० रुपये के बीच की आयवाले लोग इस क्रम में सम रूप से वितरित हैं, ऐसा लगता है कि १९५५-५६ में करीब ७२ प्रति शत आबादी की आय उस वर्ष की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (२५५ रुपये) से कम थी और कुल व्यक्तिगत आय में उनका हिस्सा ४९ प्रति शत था। इस प्रकार १९५५-५६ में करीब २८ प्रति शत आबादी—जिसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से अधिक है—का हिस्सा कुल व्यक्तिगत आय के ५० प्रति शत से अधिक था। भिन्नात्मक वर्गों (फ्रैक्टाइल ग्रुप) पर आधारित विश्लेषण से आय-वितरण की असमानता की सीमा का और स्पष्ट विवरण मिल जाता है। मासिक प्रति व्यक्ति आय के अनुसार वर्गीकृत करने से १९५५-५६ में आबादी के उच्च १० प्रति शत की आमदनी आय-कर देने से पूर्व की कुल आय (अर्थात् व्यक्तिगत आय) का ३४ प्रति शत थी; उच्च ५ प्रति शत की २३ प्रति शत और उच्च एक प्रति शत की तो ११ प्रति शत थी, जबकि निचले २५ प्रति शत ने आय के १० प्रति शत में ही हिस्सा बढ़ाया। कर देने के बाद वही आय (अर्थात् जिस आय को खर्च किया जा सकता है) पर विचार करने से अवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। इसके सिवाय और किसी बात की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कुल आबादी में कर-दाताओं का अनुपात बहुत कम है।

— रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड लेवरेज ऑफ लिविंग, पार्ट १ (डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ एण्ड कंसेंट्रेशन ऑफ इकनॉमिक पावर)

गोबर गैस संयंत्र : विभिन्न उपयोग और समाज पर प्रभाव

जशभाई झ. पेटल

गोबर गैस संयंत्र ग्रामीणों को ईंधन का सस्ता स्रोत उपलब्ध करेगा। गोबर से गैस तैयार करके जलाने से उपलो की अपेक्षा अधिक तेज आँच प्राप्त होती है।

गोबर गैस संयंत्र मुख्यतः रूढ़ी पदार्थों का यंत्र है। यह उसी तरीके का इस्तेमाल करता है, जोकि प्रकृति अस्थायी प्राकारिक कचड़ा पदार्थों के इस्तेमाल के लिए करती है। प्राकारिक कचड़ा पदार्थ किमी भी प्रकार का क्यों न हो, उससे अन्ततः मुख्यतया तीन गैसों—मीथेन, कार्बन डाइक्साइड और हायड्रोजन—का मिश्रण, जिसमें नाइट्रोजन, हायड्रोजन सल्फाइड और अन्य गैसों की भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा रहती है, और ह्यूमस की तरह ही करीब-करीब बिल्कुल काले रंग का स्थायी ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। गैस का उपयोग घरेलू अथवा औद्योगिक जलावन के रूप में किया जाता है तथा स्थायी अथवा पाचित पदार्थ ह्यूमस और अधिक नाइट्रोजनवाली खाद होता है। सम्पूर्ण किण्वन विज्ञान के

इस गैस का उष्मीय मान प्रति घनफुट ५५० ब्रिटिश थर्मल यूनिट (ब्रि थ यू) है। जलने पर इससे नीली अज्योतिष्मान ज्योति निकलती है, जिसका तापमान १०,००० फर्नहाइट से भी अधिक होता है। इस गैस का २५० घनफुट एक मन (८२ पाँड या ३७ २ किलो-ग्राम) जलावन लकड़ी का काम देता है। इससे कालिख नहीं लगती। इसका इस्तेमाल विशेष प्रकार के बर्नर में किया जा सकता है और बर्नर में पूर्ण रूप से जलाये जाने पर कोई गंध भी नहीं निकलती। इसका इस्तेमाल मेटलवाली गैसबत्तियों जलाने में भी किया जा सकता है। अब तक जो गैसबत्तियाँ उपलब्ध हैं, वे बड़ी असंतोषजनक हैं। उनका प्रारम्भिक तथा रख-रखाव खर्च अधिक है। अतः गैस-बत्तियों का उपयोग वाछनीय

जलावन	उष्मीय मान (प्रति पाँड किलो कैलरी)	योग्यता	मूल्य		प्रभावी मूल्य (१,००० किलो कैलरी)
			प्रति मन (रुपये)	प्रति पाँड (पैसे)	
मृदु कोयला	२,८६०	२८	२६०	३१७	३०३
लकड़ी का कोयला	३,१५०	२८	८२५	१०००	११४०
लकड़ी	२,१४०	१७ ३	२००	२४४	६५९
उपले	९६७	११०	२०० मन	२४४	२२७
मिट्टी का तेल	४,९०३	४८	१७५ गैलन	८१९०	९३५
बिजली		७६	१० पैसे		
			किलोवाट		१५४०
कोयले की गैस	११९ किलो कैलरी				
	प्रति घनफुट	६०	४५० एक हजार घनफुट		६३
गोबर गैस	१४२ ,,	६०	३०० एक हजार घनफुट		३५२

क्षेत्र में यह प्रक्रिया इस प्रकार बिल्कुल निराली है कि शुद्ध सवर्धन बनाये रखने की जरूरत नहीं तथा किण्वन के लिए कच्चे माल के आवपन और अनुवर्गीकरण की आवश्यकता नहीं। वात-निरपेक्षित णचन के इस विघेन गुणने सगल वात-निरपेक्षित गैस संयंत्र का विकास सम्भव बनाया। चन्द शतों के पूरा कर दिये जाने पर सवर्धन में गति आ जाती है तथा वह अच्छी तरह काम करता है।

नहीं है। उत्तम गैसबत्तियाँ तैयार करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

सबसे सस्ता जलावन

गोबर गैस संयंत्र में प्रति १,००० घनफुट गैस उत्पादन पर तीन रुपये खर्च होने हैं। इस दर से तो यह भारत का सबसे सस्ता जलावन है। उक्त तालिका में विभिन्न जलावनों का मूल्य और प्रभावी मूल्य दिया गया है।

उपर्युक्त तालिका में यह भी देखा जा सकता है कि जहाँ जलावनो में उपले सबसे महँगे हैं, गोबर से ही तैयार गैस सबसे सस्ती है।

सौ पौण्ड ताजे गोबर में २० पौण्ड सूखा पदार्थ होता है। इससे ३० पौण्ड उपले तैयार होते हैं। यदि ये ३० पौण्ड उपले जलाये जाये, तो ३,१९११० किलो कॅलरी प्रभावी उष्मा देगे। जब गोबर गैस सयत्र में १०० पौण्ड ताजा गोबर पाचित होता है तो औसतन ७० घनफुट गोबर गैस मिलती है। रसोई बनाने में इस ७० घनफुट गोबर गैस का इस्तेमाल करने पर ५,९६४ किलो कॅलरी प्रभावी उष्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार गोबर गैस में बदल दिये जाने पर उसी गोबर से उसके उपले की तुलना में ८६९ प्रति शत अधिक प्रभावी उष्मा मिलती है। गोबर में जितना सूखा पदार्थ रहता है, उसका सिर्फ २० प्रति शत ही गैस में परिवर्तित होता है। इस प्रकार सिर्फ ४ पौण्ड सूखा पदार्थ ही जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और १६ पौण्ड खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बच जाता है। जब उपले जलाते हैं तो सिर्फ राख ही खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बच जाती है।

खाद में नाइट्रोजन

खाद के गड्ढो में जब १०० पौण्ड ताजा गोबर रखा जाता है तो उसमें का आधा सूखा पदार्थ समाप्त हो जाता है, और फिर १० पौण्ड सूखा पदार्थ ही पकी खाद के रूप में बच पाता है। बाकी १० पौण्ड सूखे पदार्थ गैस बन कर हवा में उड़ जाते हैं। जैसा कि पहले देखा जा चुका है कि जब गोबर को गैस में बदला जाता है तो १६ पौण्ड सूखा पदार्थ खाद के लिए बच जाता है और इस प्रकार ६० प्रति शत अधिक खाद प्राप्त होता है।

गोबर गैस सयत्र से प्राप्त खाद का नाइट्रोजन के लिए विश्लेषण किया गया और उसमें कम से कम १५ प्रति शत नाइट्रोजन पाया गया। बाड़े की खाद के सूखे पदार्थ में अधिक से अधिक १ प्रति शत नाइट्रोजन होता है। इस प्रकार प्रत्येक १०० पौण्ड ताजे गोबर

से बाड़े की खाद में ०.१ पौण्ड नाइट्रोजन बच जाता है और सयत्रवाली खाद में ०.२४ पौण्ड।

गाँव में मानव मल-मूत्र बिल्कुल बेकार जाता है। यदि गाँव में १०० व्यक्तियों के लिए शौचालयों से लगे गैस सयत्रों का इस्तेमाल किया जाय तो प्रति दिन १०० घनफुट गैस अथवा प्रति वर्ष ३६,५०० घनफुट गोबर गैस प्राप्त की जा सकती है, जोकि २८२ रुपये कीमत की १४१ मन जलावनवाली लकड़ी के बराबर है। सौ व्यक्तियों के मल-मूत्र से गोबर गैस सयत्र में जो खाद तैयार होगी, उससे प्रति वर्ष २०० रुपये मिलेंगे। इससे गाँव में प्रति १०० व्यक्ति पीछे कुल ४८२ रुपये अथवा मोटे तौर पर ४७५ रुपये प्राप्त हो जाते हैं।

अन्य लाभ

मैदान में शौच करने के बदले शौचालयों का उपयोग करने के लिए, इसके समाजिक पहलू पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। गाँव की महिलाएँ शौच के लिए सुबह अंधेरे और शाम ढलने के बाद मैदान में जाया करती हैं। उन्हें दिन-भर परेशानी उठानी पड़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण यानी इससे भी अधिक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि गोबर गैस सयत्र भगी का काम भी कर देता है। सयत्र में तैयार खाद कुछ समय बाद गब-रहित हो जाती है। कभी भी मल-मूत्र ढोना नहीं पड़ता—वह गोबर गैस सयत्र के पाचित में चला जाता है और वहाँ से पूर्ण पाचित काली खाद के रूप में बाहर आता है।

गाव में सूखे ओर ताजे मल-मूत्र से फैलनेवाले कीटाणुओं को पूर्णतः रोकना स्वास्थ्य-मफाई की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिर, गोबर गैस सयत्र के उपयोग से कड़े-कचड़े और खाद के गड्ढो में पैदा होनेवाली मक्खियों का अभिजनन बिल्कुल बन्द हो जाता है। गोबर गैस सयत्र में निकलनेवाले पाचित पदार्थों पर न तो मक्खियाँ बैठती हैं और न ही वे मक्खियों को जन्म देते हैं। फिर, पाचित खाद पर मक्खियाँ जिन्दा भी नहीं रहती।

उपले अथवा लकड़ी के बदले गोबर गैस का इस्तेमाल करनेवाले परिवारों को और भी कई लाभ होते हैं, जैसे, उपले बनाने की मेहनत बच जाती है, रसोई घर साफ सुथरा रहता है और रसोई बनाना आनन्ददायक हो जाता है।

बम्बई १० फरवरी १९६४

किसानों के लिए उर्वरक

मगदेसन बालसुब्रह्मण्यन

इस लेख में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनकी कीमत कम करने, किसानों को उनके उपयोग की पूर्ण जानकारी देने के लिए कार्रवाई करने तथा भूमि-विश्लेषण की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

भारतीय किसान कई कारणों से बाछित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग नहीं करते। उदाहरणार्थ, किसानों को और अधिक ऋण सुविधाएँ देने तथा योग्य वितरण संगठन खड़ा करने एवम् उर्वरकों के उपयोग की शिक्षा देने की आवश्यकता है। भारतीय किसान को तो अभी यह भी समझाना बाकी है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का क्या महत्व है तथा यह कि पौध को पौष्टिकता प्रदान करनेवाले इन अत्यावश्यक तत्वों की राष्ट्रीय खपत निराशाजनक है। जब तक पौध-पौष्टिक-तत्वों की वर्तमान दर को नहीं बढ़ाया जाता, तब तक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किये जा रहे विशेष प्रयासों तथा अनुकूल बारिश के बावजूद तीसरी पंचसाला योजना के बाकी समय में कुल कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि की औचित्यपूर्ण आशा नहीं कर सकते। अतः तत्काल आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों के कृषि विभाग सतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए और अधिक प्रचार व प्रदर्शन करें। यूरिया जैसे उर्वरकों की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहक कदम उठाने आवश्यक है। ऐसा उर्वरकों के इस्तेमाल सम्बन्धी फिल्में दिखा कर किया जा सकता है।

उर्वरकों की पूर्ति

यदि खाद देने के मौसम के पूर्व ही खुदरा बिक्री भण्डारों में उर्वरकों का स्टॉक भर दिया जाय और उनके बिक जाने पर समय रहते अच्छी पूर्ति कर दी जाय, तो बिक्री बढ़ेगी और फलतः कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। मोंग और उपभोग लक्ष्य के अनुसार उर्वरकों के परिवहन को गति बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने

हाल ही में चन्द रियायते लागू की हैं, जैसे ५०० किलोमीटर तक उर्वरकों की सड़क-परिवहन दर की प्रतिपूर्ति करना, गैर मौसम में उर्वरकों की कीमत में अमोनियम सल्फेट पर प्रति टन ढाई रुपये तथा यूरिया पर प्रति टन चार रुपये प्रति माह छूट (रिबेट) देना। राज्यों को स्वयम् ही इन रियायतों का उपयोग सुदूर गाँवों में स्टॉक जमा करने तथा भविष्य में बन्दरगाहों में आनेवाले उर्वरकों को शीघ्र गोदामों में पहुँचाने की व्यवस्था करने के लिए करना चाहिये। राज्य सरकारों को इन रियायतों का सर्वोत्तम उपयोग करने योग्य बनाने हेतु भारत सरकार भी कार्यालयी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठा सकती है।

किसानों को प्रशिक्षण

नेत्रजनीय उर्वरकों के वितरण का एकाधिकार सहकारी समितियों को सौंपने की सरकारी नीति के अवाछित परिणाम निकलने की आशा है, क्योंकि इससे सहकारी समितियों का सिर्फ अनुचित प्रश्रय ही मिलेगा। अतः इस दृष्टि से कि किसान धीरे-धीरे अधिक मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने लगें, सरकार को निजी क्षेत्र की सेवाएँ लेने में भी हिचकना नहीं चाहिये। सरकार जितनी ही जल्दी रासायनिक उर्वरकों के योग्य वितरण हेतु सहकारी विभाग के साथ ही साथ उर्वरक निर्माताओं और वितरकों की सेवाओं का उपयोग करने लगेगी, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में उतना ही अच्छा होगा।

करीब-करीब सभी उदियमान देश अपनी सारी प्रशिक्षण व्यवस्थाएँ औद्योगिक तकनीकों के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसानों को अकेला छोड़ देते हैं। आधुनिक कृषि में उद्योग की तरह प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कृषि विभाग की समस्याओं का सही उत्तर है पूर्ण जानकारी और प्रशिक्षित किसान। कृषि में वास्तविक मोड़ तो बड़े पैमाने पर किसानों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के आधार पर ही लाया जा सकता है।

किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों के मुख्य वाहक उर्वरक उद्योग को भी स्वयम् प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व समझना है और उसमें भाग लेना है। किसान प्राणारिक खाद के उपयोग तथा उसी तरह के जो अन्य समाचार देंगे, उनसे उर्वरक उद्योग जो दिलचस्पी लेगा उससे कहीं अधिक कीमत बसूल हो जायेगी। यह अत्यावश्यक है कि उर्वरक के उत्पादन में जो इतनी अधिक लागत लगती है, वह घटा कर कम से कम की जाय। भारतीय उर्वरक निगम को भी शीघ्र ही प्रदर्शनो और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये किसानों को उर्वरकों का प्रयोग सिखाना ही चाहिये। उर्वरक सम्बन्धी वैज्ञानिकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मिट्टी विश्लेषण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उपयुक्त मात्रामें उर्वरकों का प्रयोग असम्भव-सा हो जाता है। अतः किसानों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिये कि उर्वरक प्राप्त करने के लिए वे अपने खेतों की मिट्टी का विश्लेषण प्रस्तुत करें। इस काम में उर्वरक उद्योग अगुआई कर सकता है।

देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु जबकि उर्वरकों की माँग तेजी से बढ़ती जा रही है, किसानों को कम से कम कीमत पर उर्वरकों की पूर्ति कराना भी कृषि अर्थ-व्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि न सिर्फ तेजी से उर्वरकों का उत्पादन बढ़े, बल्कि लागत भी यथा सम्भव कम से कम हो। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं और प्रस्तावित नयी इकाइयों को उर्वरकों की बढ़ती माँग की पूर्ति करनी चाहिये।

आम तौर पर उर्वरक उद्योग अपने निवेश के अनुसार अधिक लाभ प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी बुनियादी लागत अधिक है। विशेष कर भारत में उर्वरक परियोजना आरम्भ करने में विदेशों की अपेक्षा अधिक पूँजी लगती है, क्योंकि भारत कारखाने के लिए अधिकांश यंत्र-संरजाम आयात करता है, जिसके लिए विदेशी

इजीनियरिंग फर्मों को अधिक मुनाफा देने के अलावा परिवहन, आयात शुल्क, बीमा का खर्च आदि भी चुकाना पड़ता है। मौजूदा इकाइयों में उर्वरकों की उत्पादन लागत कम करने के लिए निम्न सुझाव दिये जाते हैं

१ यूरिया जैसे उच्च सांद्रतावाले उर्वरकों के उत्पादन की कोशिश की जानी चाहिये। न्यून-सांद्रतावाले उर्वरकों का नाइट्रोजन तत्व २०.५ से बढ़ा कर धीरे-धीरे २६ प्रति शत तक लाया जा सकता है। उच्च सांद्रतावाले उर्वरकों का उपयोग करने से लागत भी कम होगी।

२ अभी अमोनियम सल्फेट को छोड़ कर, जोकि एक बोरे में १०० किलोग्राम भरा जाता है, बाकी सभी उर्वरक एक बोरे में ५० किलोग्राम ही भरे जाते हैं। सभी उर्वरकों के लिए १०० किलोग्राम की पैकिंगवाले बोरे का इस्तेमाल अच्छा रहेगा। इससे पैकिंग-खर्च में बचत होगी।

३ छुट्टे पुर्जों और भंडार की वस्तुओं की मूँची छोटी से छोटी की जानी चाहिये। यह उचित सूची-नियंत्रण तथा सम्प्राप्ति समय में कमी करके की जा सकती है।

४ मजदूरी और व्यवस्थापन खर्च को न्यूनतम रखना नितान्त आवश्यक है, जोकि उत्पादन लागत के महत्वपूर्ण बड़े खर्च हैं।

नये कारखानों अथवा नयी परियोजनाओं के मामले में लागत कम करने के लिए ये सुझाव हैं (१) कारखाना ऐसी जगह में स्थापित किया जाना चाहिये कि कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन पर अधिक खर्च न बैठे अर्थात् कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल भेजने की दूरी अधिक न हो। यदि उर्वरक कारखाने वैसे स्थानों में स्थापित किये जायें जहाँ कच्चे माल और तैयार माल को अधिक दूर तक लाना-ले-जाना पड़े, जिससे कि माल-भाड़े का खर्च बहुत ज्यादा हो, तो रेलवे अधिकारियों को नीति स्वरूप अधिक रियायती दरे लागू करनी चाहिये, और (२) यह वाछनीय है कि अब तक जितनी बड़ी परियोजनाएँ हमने आरम्भ की हैं, उनसे बड़ी परियोजनाएँ आरम्भ की जायें।

उन्नत धान-कुटाई चक्की

रा. कृ. श्रीवास्तव, एस. वाय. नन्दनवार और भा. य. राव

धान कुटाई चक्की में हाल ही में चन्द सुधार उसकी योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से किये गये हैं। इस सुधरी चक्की में २० किलो ग्राम धान की कुटाई करने से ज्ञात हुआ कि इसकी कुटाई क्षमता ४० किलोग्राम धान प्रति घंटा है, टूटन कम होती है और तैयार चावल में धान का प्रातिशत्य भी न्यूनतम रहता है।

जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला ने एक हस्त-चालित चावल कुटाई यंत्र तैयार करने के लिए काफी काम किया है, जिसमें धान की कुटाई करने के लिए रबड़-युक्त बेलन लगा है। परन्तु अब तक यह यंत्र जितना विकसित हो पाया है उससे धान कूटनेवाली सामान्य चक्की से अधिक लाभ नहीं मिलता।

हाल ही में इसे अन्य कुटाई यंत्रों से अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें कुछ सुधार किये गये हैं। सुधरी चक्की में लकड़ी के दो पाट १४ इंच व्यास और ३ इंच

सफाई का काम मजदूरिन करती है। पूर्ण कार्य तीन सोपानों में किया जाता है। प्रारम्भिक कुटाई के बाद धान और भूसी को मजदूरिन अलग-अलग कर लेती है और धान को फिर से चक्की में डाल देती है। दूसरी बार कुटाई करने के बाद भी जो धान बच जाता है, उसे फिर चक्की में डालते हैं। बचे हुए धान तथा प्रति कुटाई में लगे समय का विवरण तालिका १ में दिया गया है।

बीस किलोग्राम धान की कुटाई करने में लगा समय और कुल शेष धान का विवरण तालिका २ में दिया गया

तालिका १

प्रत्येक सोपान में कुटाई में लगा समय और शेष धान

सोपान क्रम	प्रारम्भिक धान (कि.ग्रा.)	चावल (प्रातिशत्य)	टूटन (प्रातिशत्य)	धान (प्रातिशत्य)	भूसी (प्रातिशत्य)	कुटाई में लगा समय (मिनट)	सफाई तथा धान-भूसी अलग करने में लगा समय (मिनट)
१	२० ०	५१ ५०	२ २५	२७ ००	१९ २५	२३	५०
२	५ ४	४३ ५	१ ९	३८ ९	१५ ७	५	१२
३	२ १	५७ २	५ ९	१९ ०	१७ ९	२	८

तालिका २

२० किलोग्राम धान की कुटाई में लगा समय और कुल शेष धान

चावल (प्रातिशत्य)	टूटन (प्रातिशत्य)	धान (प्रातिशत्य)	भूसी (प्रातिशत्य)	कुटाई समय (मिनट)	सफाई और अलग करने में लगा समय (मिनट)
६९ २	३ ४	२ ०	२५ ४	३०	७०

मोटाई के होते हैं तथा उनमें विशेष किस्म के छिद्र किये होते हैं। एक पाट स्थिर रहता है और दूसरा पाट एक गियर के जरिये हथके से जुड़ा होता है। धान-प्रशोधन करते वक्त यह चाक सहज ही प्रति सेकण्ड ३५० चक्कर लगा सकता है। इस चक्की की योग्यता दर्शाने के लिए इसमें २० किलोग्राम धान कूटने का जो परीक्षण किया गया, उसके आकड़े ऊपर प्रस्तुत हैं।

सुधरी चक्की को एक पुरुष श्रमिक चलाता है और

है। उपर्युक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट हो जायगा कि सुधरी चक्की की धान कुटाई क्षमता प्रति घंटे ४० किलोग्राम है और टूटन का प्रातिशत्य भी बहुत कम (करीब ३ से ४ प्रति शत) है। इस किस्म की चक्की के ये लाभ हैं (१) अधिक कुटाई क्षमता, (२) कम टूटन, और (३) तैयार चावल में धान का प्रातिशत्य न्यूनतम।

इसमें सुधार के लिए और प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अहमदनगर जिले में गाँवों का आर्थिक सर्वेक्षण और आयोजन

मधुसूदन द. साठे

महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के सत्तासी गाँवों के आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़े यह दर्शाते हैं कि करीब एक तिहाई भूमि परती है, मिचित भूमि का अनुपात नगण्य है, औसत खेत बहुत छोटे हैं और प्रति एकड़ उत्पादकता कम है, जिसके परिणाम-स्वरूप गरीबी की जड़ें बहुत गहरी जम गयी हैं। स्थानीय लोगों की आर्थिक अवस्था सहकारी अथवा सामूहिक रूप में ग्रामीण स्रोतों—वन्य स्रोत भी शामिल है—के उपयोग का आयोजन कर, जिसमें कि रोजगारी की व्यवस्था पर अधिक जोर रहेगा, सुधारी जा सकती है।

अगस्त १९६२ में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के अकोला तालुके में ८७ गाँवों का सर्वेक्षण किया गया। इन गाँवों का कुल क्षेत्रफल १९,४८,८६१ एकड़ अथवा ३०४ ४ वर्ग मील है। इसमें से खेती के अन्तर्गत १,०४,९४७ एकड़ अथवा १६३ ७ वर्ग मील क्षेत्र है, जोकि कुल क्षेत्र के आधे से अधिक है। फसलों के अनुसार खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का वितरण इस प्रकार है

फसल का नाम	फसल के अन्तर्गत क्षेत्र (एकड़ में)
धान	१७,३७७
नाचनी	१७,८१२
खुरसानी	५,६०५
बाजरा	३,९००
सावा	४,१५५
मूंगफली	२,९३०
बरी	२,२८२
ज्वार	५९१
उड़द	१,६८८
कुलीय	५,०५५
मोठ	३२३
मूग	३६
गेहूँ	३,६९३
चना	२,१४२
गन्ना	१२२
रहर	७९
टमाटर	१०४
आलू	१४
तम्बाकू	५
घास	अप्राप्य
तरकारी	अप्राप्य
कुल	६७,९१३

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि खेती के अन्तर्गत

जितनी जमीन है, उसमें आधी से अधिक तो धान और नाचनी फसलों के अन्तर्गत है।

जगली और सिंचित क्षेत्र

इस क्षेत्र में जगली इलाका ६३,७६० एकड़ अथवा ९९ ६१ वर्ग मील है। चरागाह १५,७१६ एकड़ अथवा २४ ७३ वर्ग मील है। परती भूमि ६९,६९१ एकड़ अथवा १०८ ८ वर्ग मील है। उपर्युक्त आकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि कुल भूमि का करीब एक-तिहाई खेती के अन्तर्गत है, करीब एक-तिहाई जगल है और एक-तिहाई से कुछ अधिक परती भूमि है।

इन गाँवों में मिचित क्षेत्र, नहर-क्षेत्र और कुआँ सिंचाई-क्षेत्र वृत्त ही थोड़े हैं—क्रमशः पाँच एकड़, छ एकड़ और ३३ से ३५ एकड़ अर्थात् कुल ५० एकड़ से भी कम है।

प्रति एकड़ धान की पैदावार १० से १३ मन है। पैदावार में धान के बाद खुरसानी का नाम आता है। खुरसानी फसल का औसत उत्पादन ५ से ६ मन है। अन्य फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन ५ मन से कम है। शायद ही कभी इस औसत से अधिक उत्पादन होता है।

कृषि कार्य बारिश पर निर्भर है और इस तालुके में बारिश २० इंच से २५० इंच तक होती है। परन्तु अकोला तालुके के डगन भाग में औसतन करीब ४० इंच बारिश होती है, जोकि धान की खेती के लिए अनुकूल है।

निम्न तालिका में यह बताया गया है कि खेती के अन्तर्गत कुल भूमि विभिन्न जोतदारों में किन आकार-वर्गों में बंटी है

जोत का आकार	खेती करनेवाले परिवारों की संख्या
१ - १ ९९	१५४
२ - २ ९९	—
३ - ३ ९९	१,२७५
४ - ४ ९९	२,८६०
५ - ५ ९९	२,४१९
६ - ६ ९९	१,८५४
७ - ७ ९९	१,७६२
८ - ८ ९९	५६
९ - ९ ९९	४६४
१० - १० ९९	१००
११ - ११ ९९	१३९
१२ - १२ ९९	—
१३ - १३ ९९	४१
१४ - १४ ९९	—
१५ - १५ ९९	—
१६ - १६ ९९	४३
१७ - १७ ९९	५१
१८ और ऊपर	२०

बम्बई प्रान्त सहकारी बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार खेतिहर-परिवारों की औसत जोत करीब ३ ५ एकड़ होती है, जबकि १९४७ में यह औसत (पाँच व्यक्तियों के खेतिहर-परिवार के लिए) ८ से २० एकड़ थी। उपर्युक्त तालिका से यह प्रकट है कि अधिकांश कृषक परिवारों के पास तीन से आठ एकड़ तक खेत है।

इस क्षेत्र में ६९,०२५ एकड़ भूमि में खेती होती है। जोकि जोत-योग्य कुल भूमि से ३७,००० एकड़ कम है। इस अन्तर के कई कारण हैं। कभी-कभी खेती के अन्तर्गत भूमि को एकदम ठीक-ठीक नहीं नापा जाता, परन्तु भूमि को भी खेती की जा रही भूमि में जोड़ दिया जाता है तथा चरागाह के रूप में भी जब इस भूमि का उपयोग किया जाता है तो यह अनगिनी रह सकती है। यदि हम

इन्हे ध्यान में रखें तो खेती योग्य भूमि और वस्तुतः खेती की जा रही भूमि के सांख्यिकी आकड़ों में जो अन्तर नजर आता है, उसका कारण सहज ही समझ में आ सकता है।

निम्न तालिका में फसलों का प्रति एकड़ मूल्य (रुपये में) दिया गया है

आय (रु में)	एकड़	एकड़ का प्रातिशाल्य
१ - २४ ९९	१३,०३८	१८ ९५
२५ - ४९ ९९	१९,३१७	२८ १४
५० - ७४ ९९	२४,९६५	३६ ६१
७५ - ९९ ९९	८,५४०	१२ ४६
१०० - १२४ ९९	२,५१२	२ ९०
१२५ - १४९ ९९	१०३	० १६
१५० - १७४ ९९	—	—
१७५ और ऊपर	८९	० १३

उपर्युक्त तालिका निश्चित रूप से यह बताती है कि प्रति एकड़ उत्पादन-मूल्य बहुत कम है। खेती के अन्तर्गत कुल भूमि के करीब ९७ प्रति शत का प्रति एकड़ उत्पादन-मूल्य १०० रुपये से कम है।

भूमि-राजस्व

इन ८७ गाँवों के भूमिधारी कुल अन्दाजन ४९,९०० रुपये भूमि-राजस्व के तौर पर देते हैं। हरे वृक्षों से ९६७ रुपये वन-रायल्टी के तौर पर प्राप्त किये जाते हैं। भूमि-राजस्व ७,७५४ भूमिधारी देते हैं। परन्तु सच तो यह है कि वस्तुतः खेती कर रहे भूमिधारियों की संख्या ११,२३२ है। पट्टे (लीज) पर खेत देनेवाले खेतिहर परिवारों की संख्या २२५ है। करीब २,९७३ खेतिहर परिवार हैं, जोकि अपने खेत जोतते हैं, परन्तु उनके आकार छोटे होने के कारण उन्हें पट्टे पर भूमि लेनी ही पड़ती है। हम यो भी कह सकते हैं कि ऐसे खेतिहर परिवारों की संख्या काफी बड़ी है—कुल खेतिहर परिवारों की करीब एक-तिहाई—जोकि अपने खेत तो जोतते हैं परन्तु वे उनके लिए अपर्याप्त हैं। आदिवासी संस्कृति के अनुरूप भूमि-रहित किसान परिवारों की संख्या नहीं के बराबर है—सिर्फ २७५। इनमें से कास्तकारों की संख्या (जोकि पट्टे पर भूमि लेते हैं) ४७ है। वन्य

भूमि में खेती करनेवालों की संख्या १,०१३ है और वे वन विभाग को राजस्व रूप में २,४७८ रुपये देते हैं।

सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार इन ८७ गाँवों की कुल आबादी ५७,५६१ है। सन् १९५१ की जनगणना से यह संख्या १२,०७१ अधिक है। अकोला तालुके की आबादी इन ८७ गाँवों को लेकर, १९५१ की जनगणना के अनुसार ९६,०७४ थी और १९६१ की जनगणना के अनुसार १,१७,७९५ है अर्थात् आबादी में २१,७२१ लोग बढ़ गये हैं।

शिक्षितों की संख्या इस प्रकार है पुरुष— ७,८८७ (अशिक्षित ८,२६१) और महिलाएँ— ३,२५६ (अशिक्षित—१३,३१२)।

अच्छी अवस्थावाले घरों की संख्या ९,८८२ है। गिरे अथवा मरम्मत की जरूरतवाले घरों की संख्या १,७२९ है। इन ८७ गाँवों में कुल ११,५८२ परिवार हैं। इस प्रकार प्रति परिवार सदस्यों की औसत संख्या पाँच से छ तक है।

कृषि से आय

निम्न तालिका में प्रति परिवार को कृषि से होनेवाली औसत वार्षिक आय का विवरण देने की कोशिश की गयी है

आय	आय करनेवाले परिवारों की संख्या
१ — ४९ ९९	१९६
५० — ९९ ९९	४८३
१०० — १४९ ९९	९३२
१५० — १९९ ९९	१,३६१
२०० — २४९ ९९	१,२१५
२५० — २९९ ९९	९०६
३०० — ३४९ ९९	१,०९०
३५० — ३९९ ९९	१,७०५
४०० — ४४९ ९९	३७५
४५० — ४९९ ९९	४९९
५०० — ५४९ ९९	५०६
५५० — ५९९ ९९	८१
६०० — ६९९ ९९	२०४
७०० — ८००	१,४२९
कुल परिवार	१०,९८२

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि करीब ९० प्रति शत कृषक परिवार खेती से आय करते हैं, जोकि वार्षिक ६०० रुपये से कम है। पाँच से छ सदस्योवाला औसत परिवार इस अपर्याप्त आय पर मुश्किल से ही जिन्दा रह सकता है। आय सम्बन्धी ये आंकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि ग्रामीण आदिवासी समाज में गरीबी की जड़े कितनी गहरी हैं। यहाँ प्रस्तुत ये सांख्यिकी आंकड़े निश्चित रूप से इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि जब तक वर्तमान कृषिक धंधे को जीविका के अन्य साधनों से पूरित नहीं किया जाता, इस आदिवासी समाज के लिए सम्माननीय जीवन-स्तर प्राप्त करना मुश्किल ही है।

कृषि से प्रति व्यक्ति औसत आय निम्न तालिका में दी गयी है

आय (रु में)	लोगों की संख्या	आबादी का प्रतिशत
१ — २४ ९९	९,९८४	१७ ७४
२५ — ४९ ९९	१३,७५२	२४ ४४
५० — ७४ ९९	१३,२७०	२३ ६९
७५ — ९९ ९९	१०,३८२	१८ ४५
१०० — १२४ ९९	८,५४१	१५ १८
२५ — १४९ ९९	८२५	१ ४७
१५० — १७५	६७५	१ २०

इन आंकड़ों से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि कुल आबादी के करीब ८५ प्रति शत लोग कृषि में ही आय करते हैं, जोकि वार्षिक १०० रुपये से कम है।

मवेशियों की आबादी निम्न तालिका में दी गयी है

मवेशी	संख्या
शुद्ध नस्ल के सांड	६९
बैल	१३,६२६
गाय	२२,९४१
भैंसा	३,८६७
भैंस	३,४७६
बकरियाँ	१६,१२०
खच्चर	१०१
घोड़े	५६
मुर्गिया (देशी)	३७,६३६
मुर्गियाँ (निदेशी)	८९

औसत रूप में इस क्षेत्र के प्रत्येक कृषक परिवार के पास एक बैल और दो गायें हैं। अकोला तालुका डागी नस्ल के भवेशियों के लिए प्रसिद्ध है।

परन्तु सर्वोत्तम डागी नस्ल के साड़ करीब ७० ही हैं। इसका यह अर्थ है कि इस क्षेत्र के अभी मूल्यवान् भवेशी नोतो पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता।

देशी जाति के पालतू पक्षियों की संख्या ३७,६३६ है। इस प्रकार प्रति परिवार पीछे औसतन ३ से ४ पक्षी है। इसकी तुलना में उन्नत नस्ल के पक्षियों की संख्या सिर्फ ९० है, जोकि निश्चय ही नगण्य है। पक्षी-पालन अपेक्षाकृत महज है और इस प्रकार पक्षी-पालन के लिए बड़े पैमाने पर क्रमबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता है, ताकि आय का सहायक-स्रोत उपलब्ध हो सके। यदि पक्षियों की नस्ल सुधरती है और उनकी बीमारियों के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुसंधान किया जाता है तथा बिक्री की सहकारी व्यवस्था की जाती है, तो पक्षी-पालन की सफलता के आधार दिखायी देते हैं।

पूरक धंधों की मांग

फिर भी, आम तौर पर यह तो कहा ही जा सकता है कि अधिकांश गाँवों में सड़के, साल भर पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल की इमारत और कृषि के अलावा जीविका के अन्य साधन नहीं हैं, फिर आलोच्य सभी गाँवों में स्वास्थ्य-सफाई पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। मार्को की बात तो यह है कि इन सभी गाँवों ने जीविका के लिए सहायक धंधे उपलब्ध करने की मांग की है। अधिकांश गाँवों ने सड़क निर्माण, स्कूली इमारत और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में कुओं की मांग की है।

गरीबी की सीमा

इन गाँवों में भी देश के अन्य गाँवों की तरह ही घोर गरीबी है। इन गाँवों में आर्थिक परिवर्तन की पहल और विकास को करीब-करीब असम्भव बनाये रखनेवाली बुनियादी बाधाएँ हैं छोटे-छोटे गाँवों में कम उपजाऊ

मिट्टी पर बहुत अधिक निर्भरता, जैसे-तैसे निर्वाह करनेवाले लोग, घोर गरीबी और अज्ञानता, साक्षरता का न्यूनतम प्रातिशत्य, प्राथमिक तकनालाजी, परम्परागत दस्तकारों और ग्रामीण कारीगर वर्गों की भी कमी, गाँवों के बीच संचार की कमी और फलतः सामाजिक सलाह की कमी।

मूल समस्याएँ दो हैं (१) सांस्कृतिक पृथक्त्व की समस्या—हमें ऐसी प्रक्रिया निकालनी है जोकि आदिवासीयों की सांस्कृतिक पद्धति और नयी आर्थिक पद्धति को अधिक विकसित समाज की पद्धतियों से समजित कर सके, और (२) आर्थिक विकास की समस्या। इन दो बुनियादी बातों का अर्थ यह है कि परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी व्यापक होनी ही चाहिये कि सम्पूर्ण आदिवासी समाज उसके अन्तर्गत आ जाय। इसके साथ ही चयन की स्वतंत्रता भी होनी ही चाहिये।

रीति-रिवाज

आदिवासी समाज में मुख्यतः महादेव ठाकर, कोली, तलवार और कमाठी आदिवासी संप्रदाय के लोग हैं, जोकि अकोला तालुके के डागन भाग में रहते हैं। उनकी अपनी घनी बस्तियाँ हैं। वे स्वभावतः बड़े स्वामीभक्त, सच्चे और सरल हैं। फिर अतिथि सत्कार तो उनके लिए धर्म जैसा ही है। कम उम्र में शादी और एक-पत्नी प्रथा प्रचलित है। उनका रहन-सहन गदा और अस्वास्थ्यकर है, जोकि पानी की कमी के कारण और गदा हो जाता है। इन सभी गाँवों में पीने के पानी की समस्या बड़ी गम्भीर है। फलतः करीब ७५ प्रति शत लोग चर्म-रोग से पीड़ित हैं। लोग इतने बलिष्ठ हैं कि साल के एक लम्बे भाग में अध-भस्त्रे रहने पर भी वे अपना स्वास्थ्य बनाये रखते हैं। पहाड़ी इलाके में रहने के कारण लोग मजबूत, परिश्रमी और कोई भी शारीरिक काम करने योग्य होते हैं।

खादाती प्रथा का झोलबाला

इन आदिवासियों के लिए प्रति वर्ष बारिश का मौसम सर्वाधिक व्यस्त और खर्चीला है। चूँकि धान मुख्य

फसल है, अतः इसकी बोआई बारिश के आगमन के साथ ही शुरू होती है। ये लोग तेज बारिश में दिन भर मेहनत करते हैं। यही समय है जबकि उनके पास भोजन बनाने के लिए बहुत कम अनाज होता है। इस कारण वे महाजनो की ओर खिंचे चले जाते हैं। सामान्यतः इस ऋण की, जिसे खावाती कहते हैं, जो शर्तें होती हैं वे बड़ी कठोर होती हैं।

किस हद तक शोषण होता है, उसे समझने के लिए हम ऋण सम्बन्धी कुछ तरीकों पर गौर करें। यदि जून माह में एक रुपया दिया जाता है, जोकि बारिश का आरम्भ काल है, तो बारिश के समाप्त होने पर चुकती के समय किसान को व्याज के रूप में दो सेर धान देना होता है और एक रुपया मूल अन्यथा उसे मूल और व्याज के रूप में ६ सेर धान देना पड़ता है।

मूल का सवाया व्याज

यदि एक बोरा नाचनी (अथवा नागली) उधार ली गयी तो चुकती के समय, फसल कटाई के बाद, मूल और व्याज के रूप में तीन बोरा धान देना होता है। शोषण का अन्दाज हम रुपये-पैसे में इस प्रकार लगा सकते हैं एक बोरा नाचनी की कीमत करीब ४० रुपये होती है। बारिश आरम्भ होने के समय, जबकि व्यापारियों के पास स्टॉक होता है, इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। किन्तु जब किसान खावाती ऋण चुकाता है तो अवस्था बिल्कुल उल्टी होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि करीब ४ महीने की अवधि के लिए ४० रुपये मूल का व्याज करीब ५० रुपये लिया जाता है।

यह याद रखना चाहिये कि मानवीय सम्पत्ता और सामाजिक चेतना के विरुद्ध ये लेन-देन तब होते हैं, जबकि व्यापारियों की शर्तें खेतिहर उत्पादकों के हित में नहीं होती-फसल कटाई के बाद उत्पादनों की कीमत न्यूनतम होती है, क्योंकि सारी फसल या तो खावाती ऋण चुकाने के रूप में या उसे बेच कर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद रकम हासिल करने हेतु बाजार में आ जाती है। महाजन-व्यापारी का यह जटिल

रूप, जोकि सारे भारत में फैला हुआ है इन गाँवों में भी व्याप्त है और इसका शोषक रूप तो बिल्कुल स्पष्ट है।

इस प्रकार महाजन उत्पादन का अधिक हिस्सा ले लेते हैं और खेतिहर-उत्पादकों को अधिक अन्न उत्पादित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देते। फिर, एक मौसम से दूसरे मौसम तक के लिए अतिरिक्त माल भी तो नहीं बचता।

इसके लिए आवश्यकता है बारिश के मौसम में बहुत ही मामूली व्याज पर लघु-कालीन खावाती ऋण देने की व्यवस्था करने और सहकारी आधार पर कार्यों का सगठन करने की। इस निर्णय से राज्य स्तर पर नीतियों में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि खावाती ऋण विशेष-तया उपभोग कार्यों के लिए होंगे जिनके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। खावाती ऋण वसूल करने की व्यवस्था करने हेतु सगठनात्मक कमी के कारण यह दुविधा कम से कम अकोला तालुके के लिए उतनी जबरदस्त नहीं है जितनी कि देश के अन्य भागों के लिए।

सर्वोदय योजना

खावाती ऋण के विषय में सर्वोदय योजना का अनुभव ध्यान देने योग्य है। पिछले तीन वर्षों से सर्वोदय योजना केन्द्र भंडारद्वारा झील के आस-पास के ९ विस्थापित गाँवों को व्याज-रहित खावाती ऋण देना आ रहा है। वर्ष १९६२-६३ में ६ गाँवों को ६,००० रुपये दिये गये। ये गाँव अब इन रूपों को वापस लौटा रहे हैं और व्याज-रहित होने पर भी अपनी ख़शी में व्याज स्वरूप २५ प्रति शत अधिक रकम लौटा रहे हैं।

व्याज रूप में प्राप्त यह राशि सीधे उन ग्रामीण अनाज भंडारों को इन समुदायों के पूँजी योगदान के रूप में दे दी जाती है। इस तरह ४-५ वर्ष की अवधि में ये गाँव अपने अनाज भंडार खोल सकेंगे। इनमें से एक गाँव-कोलतेम्बे-खावाती के मामले में स्वावलम्बी हो गया है। इन गाँवों तथा इनकी समस्याओं से निकटतम संबंधित व्यक्तियों से बातचीत करने के बाद यह पता लगा कि प्रत्येक गाँव को औसत रूप में ४,००० रुपये के

ऋण की जरूरत है, जबकि सर्वोदय योजना के अन्तर्गत सिर्फ २५ प्रति शत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही संभव हो सका है अर्थात् प्रत्येक गाँव को एक हजार रुपये दिये गये हैं। फिर, कभी-कभी भोजन सामग्री की थोक खरीद, भाडारीकरण और बिक्री से संबंधित कठिनाइयाँ बड़ी सकटमय हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समस्या का हल करने के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध वित्त की सहायता से प्रयोग करना आवश्यक है।

यह स्पष्ट है कि कृषि पर्याप्त आय कराने के लिए अपर्याप्त है और अधिक खेत कृषि के अन्तर्गत लाने की संभावना न्यूनतम है। कुछ स्थानों में घने जंगलों की सम्प्राप्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाया जा सकता है, परन्तु वह जमीन सामान्यतया रागी, बाई आदि जैसे मोटे अनाज पैदा करने के लिए ही उपयुक्त होगी। धान के खेतों में और वृद्धि होने की आशा नहीं है, परन्तु यदि उन्हीं खेतों में धान की फसल कटाई के बाद गेहूँ, चना आदि दूसरी फसले (जाड़े की फसले) उगाने की कोशिश की जाय तो काफी हद तक कृषि उत्पादन बढ़ने की संभावना है, परन्तु यह सब तभी संभव है, जबकि जल-स्रोतों का उपयोग किया जाय तथा किसानों को सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध की जाय।

धान मार्गदर्शी योजना

प्रचुर घाटी क्षेत्र में फल-बागवानी की संभावनाओं की जाँच करना अत्यावश्यक है। सहकारी स्तर पर उच्च सहायित फल-बागवानी प्रयोगों से कृषि सुधार में सहायता मिल सकती है।

अकोला तालुके में धान मार्गदर्शी योजना के अनुभव दिलचस्प हैं। सरकारी अधिकारियों का विश्वास था कि इस तालुके में बीस हजार एकड़ धान के खेतों में से करीब पाँच हजार एकड़ का इस्तेमाल जापानी पद्धति से धान की खेती करने में किया जा सकता है। जापानी पद्धति की तकनीकल शर्त यह है कि धान के खेतों में जल-पूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिये, और यह संभजना

बड़ा कठिन है कि जापानी पद्धति से ५ हजार एकड़ में खेती करने का लक्ष्य क्यों कर निर्धारित किया गया, जबकि इस तालुके में वैसी जमीन बहुत ही कम है जहाँ हमेशा पानी उपलब्ध हो (इस तरह की भूमि को नम भूमि कहते हैं)।

धान मार्गदर्शी योजना के प्रथम वर्ष में प्रति एकड़ ४० रुपये नकद और ३२ रुपये के उर्वरक दिये गये। परन्तु इसमें शर्त यह थी कि नकद ऋण तभी दिया जा सकता है, जबकि उर्वरक भी खरीदे जाय। उर्वरक महज ४० रुपये नकद प्राप्त करने के लिए लिये गये। किसानों का मनोवैज्ञानिक रख इस तरह विकसित हो रहा था, और अधिक अधिकारियों ने खुशी-खुशी यह विश्वास कर लिया कि लोग अधिकाधिक जापानी पद्धति को अपना रहे हैं। जापानी पद्धति की सफल प्रयुक्ति को मापने का उनका ढग निराला ही था। यो भी कह सकते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ “लक्ष्य की पूर्ति” ही थी। जापानी पद्धति को लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसे वे इस चीज से मापते थे कि उनके गोदामों से उर्वरकों के कितने बोरे किमान लेते जा रहे हैं। इस नीति के साथ भी पाँच हजार एकड़ का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। प्रथम वर्ष में सिर्फ १,२०० एकड़ क्षेत्र में जापानी पद्धति से खेती हुई। दूसरे वर्ष में और २०० एकड़ क्षेत्र उसमें शामिल किया गया। सन् १९६३ में लक्ष्य ५ हजार एकड़ से कम कर ३ हजार एकड़ कर दिया गया।

कठिनाइयाँ

धान मार्गदर्शी योजना के लक्ष्य की पूर्ति में आनेवाली सही और कल्पित कठिनाइयों में से चन्द पर हम विचार कर सकते हैं। चूँकि उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी में ऊष्मा पैदा करता है, अतः पानी की सप्लाई तो सुनिश्चित होनी ही चाहिये, और अकोला तालुका ऐसा क्षेत्र है, जहाँ बारिश में बहुत अधिक भिन्नता पायी जाती है। फिर, अनुभवी किसानों का यह कथन है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी में पैदा हुई ऊष्मा के कारण किसानों को आगामी रबी फसल के लिए मिट्टी में जो अनुकूलतम भारता चाहिये वह नहीं रहती। फलतः

जिन किसानों को धान की जापानी पद्धति से खेती करने पर खरीफ फसल में लाभ होता है, उन्हें ही रबी की फसल में घाटा उठाना पड़ता है। इस प्रकार धान के बड़े उत्पादन से जो लाभ होता है, वह रबी फसल में कमी होने से बराबर हो जाता है।

यह इलाका पहाड़ी है, जिस कारण यहाँ जल-पूर्ति की व्यवस्था अलग ही है। प्रायः पौधों में जब उर्वरक डाले जाते हैं तो वे बह जाते हैं। सरकारी अधिकारी इस कठिनाई को नहीं समझे। जापानी पद्धति से धान की खेती करने में दक्ष श्रमिकों की कमी अनुभव की गयी। फिर, तेजी से काम के मौसम में, खास कर फसल बोआई के समय, दक्ष मजदूरों की जरूरत पड़ती है। किसान वर्ग दोहरी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है—बारिश और सहकारी जन-स्रोत पर निर्भरता। फिर, किसानों की मन-स्थिति सम्पूर्ण गाँव की सहकारी श्रम-शक्ति पर परस्पर-वलम्बन की आवश्यकता को स्वीकार करने की नहीं है।

मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों पर काबू

मिट्टी के हिसाब से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरक प्रयुक्त करने के बदले गोबर खाद तथा कम्पोस्ट खाद (बाड़ा खाद) का उपयोग करना वाछनीय होगा। चूबूतरे बनाकर बीज पैदा करनेवाले तरीके में बीज हल्के पीले रंग के होते हैं, क्योंकि चूबूतरे जैसी स्थिति में पानी एक स्थान पर रुक जाता है, बहता नहीं। तथापि, बहुत संभव है कि चन्द प्रौद्योगिक और भौतिक कठिनाइयाँ मनोवैज्ञानिक हों, जिन्हें धान मार्गदर्शी योजना के जोरदार प्रचार कार्य तथा विस्तार से दूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कृषि को आधुनिक बनाने की किमी भी योजना को सफल बनाने के लिए इन मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को दूर करना ही होगा।

एक तरह से देखें तो किसानों को जापानी पद्धति में निहित तकनीकल प्रवृत्तियों को कभी ठीक से समझाया नहीं गया और न ही उन्हें इस पद्धति के विषय में ठीक से कुछ बताया गया। संभवतः यह अधिकारियों की

‘लक्ष्य पूर्ति’ की ओर नज़र का परिणाम था। तकनीकल तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि प्रचार कार्य अक्टूबर तथा नवम्बर महीने में आरम्भ किया जाय, न कि अवानी बोलने के मौसम में। हमारे यहाँ के लिए अच्छा यह होगा कि हम जापानी पद्धति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को अपना लें—विशेष कर उनको जोकि स्थानीय आबहवा, मिट्टी, जल-स्रोत आदि के लिए उपयुक्त हों—और खेती की हमारी जो वर्तमान प्रक्रिया है, उसकी विषयताओं को भी अपनाये रहे। तब इसका अर्थ होगा धान की खेती जापानी पद्धति से करने के बदले वैज्ञानिक पद्धति से करने पर जोर देना।

इन गाँवों में शीघ्र ही सिंचाई के लिए जल स्रोतों (कुएँ, नहरे, भंडारे, बाध, तालाब आदि) की खोज करने हेतु तकनीकल सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। विभिन्न सिंचाई फसलों के लिए मिट्टी की उपयुक्तता—और विशेष कर जापानी पद्धति से धान की खेती करने योग्य कुल भूमि—निश्चित की जानी चाहिये और तदनुसार ही खेती योग्य कुल भूमि को बर्गीकृत करना चाहिये। इस तरह के सर्वेक्षण से इस क्षेत्र के कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है, वे कितने ही छोटे न्यो न हों, उनकी खोज की जा सकती है।

सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए आयोजन

लगता है कि अब तक उत्पादन के क्षेत्र में ग्रामीण स्रोतों के सामूहिक अथवा सहकारी उपयोग की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। आर्थिक स्रोतों के सामूहिक उपयोग के इस विचार, जिसमें मितव्ययिता शामिल है, की कल्पना नहीं की जा सकी है और इस प्रकार फलतः इस विचार को कुल निवेश प्राथमिकताओं और सगठनात्मक योजना में शामिल नहीं किया गया है।

यह क्षेत्र आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है कि कृषि विकास की कोई भी महत्वाकांक्षी योजना, औद्योगिक विकास के लिए सहायक योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं को बाध देते हुए, इस आदिवासी आबादी को

पर्याप्त रोजगारी और आय नहीं दे सकेगी। शैक्षणिक और समाज कल्याण कार्य, स्वास्थ्य और सफाई कार्य पर हो रहे खर्च के साथ, उतने ही जरूरी है और उनके लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। इस निवेश खर्च को श्रमिक इकाइयों द्वारा न्यूनतम योग्य कार्य करने के लिए निवेश समझा जा सकता है।

रोजगारी के अवसरों का तो निर्माण होना ही चाहिये, परन्तु उसके साथ-साथ ही ग्रामीणों में इस बात के लिए भी उत्साह होना चाहिये कि वे इन निर्मित अवसरों का लाभ उठाये। अतः इन आदिवासियों में उत्तम सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाना होगा। उन्हें मदद देनी होगी, और कभी-कभी मजबूर करना होगा कि वे अपनी प्राचीन सामाजिक पद्धति से भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से बाहर निकले अन्यथा परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ वस्तुतः कठिन है।

अखाद्य तिलहनो का एकत्रण

विस्तृत रोजगार योजना बनाना भी बहुत जरूरी है। अभी अधिकांश किसानों के लिए सानाजातीय मर्दों में की गयी व्यवस्था में प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण और उत्पादन सभाव्यताओं का कोई खास अर्थ नहीं है। चूकि उत्पादन स्रोतों की बहुत कमी उनके व्यक्तिगत दुख-दर्द का मूल कारण है, अतः उनके लिए रोजगारी और आय की व्यवस्था करना ही एक मात्र रास्ता है, जोकि उन्हें कम उत्पादकता और न्यून स्रोतों के दूषित वृत्त से बचा सकता है। यह रोजगार योजना कृषि कार्य की योग्यता बढ़ाने का तरीका निकालेगी ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो।

अभी रोजगारी के चन्द अकृषिक स्रोत हैं जंगल में लकड़ी कटाई, कोयले तैयार करना, हिरदा एकत्रण, सड़क निर्माण और मरम्मत आदि। चन्द स्थानीय लोगों का यह धूमिल विश्वास है कि इस क्षेत्र के घने जंगल स्रोतों का इस्तेमाल करनेवाले कुछ लघु उद्योग गैर-

मौसमी में पर्याप्त पूरक रोजगारी दे सकते हैं। सर्वोदय योजना के अन्तर्गत अखाद्य तेल और साबुन उद्योग द्वारा दिये गये योगदान का हम जिक्र कर सकते हैं, जिसके अन्तर्गत गुलचाई (पिमा) और रत्न-ज्योति तिलहनो की खोज की गयी। भंडारदरा के आस-पास के जंगलों में उगनवाले गुलचाई में लॉरिक एसिड काफी मात्रा में होता है। अभी इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। इन तिलहनो के एकत्रण में आदिवासियों को लाभदायक रोजगारी मिलती है और इसके जरिये उन्हें सालाना ५ हजार रुपये मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में रत्न-ज्योति (जंगली अडी) उगती है। राजूर के साबुन केन्द्र ने इस तिलहन को प्रशोधित कर पाया कि साबुन निर्माण में अडी के तेल के स्थान पर इसके तेल का उपयोग किया जा सकता है। सघन जंगल सर्वेक्षण कर और भी वन्य उत्पादनों की खोज की जा सकती है।

इस क्षेत्र के जंगली स्रोतों का तकनीकल सर्वेक्षण करने से आदिवासियों के लिए रोजगारी के चन्द नये स्रोत भी खोजे जा सकते हैं। इन अतिरिक्त रोजगार स्रोतों को सहकारी आधार पर संगठित करना होगा। पिछले दशक से इस क्षेत्र में वन्य श्रमिक सहकारी सघ काम कर रहे हैं। प्रारम्भ में उन्हें स्थानीय और बाहरी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परन्तु उन्होंने सब को झेल लिया।

जंगलों का प्रबन्ध

इस सबंध में सहकारी वन्य प्रबन्ध विचार के प्रभाव का परीक्षण आवश्यक है। संरक्षित जंगलों, बागों और जंगली कृषो का प्रबन्ध और रक्षण वन्य श्रमिकों की समितियों को सौंप देना चाहिये। इससे न सिर्फ वन-विभाग का काफी प्रशासनिक खर्च बच जायेगा, बल्कि सहकारी संगठन के सफल कार्य संचालन हेतु मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने में भी बहुत मदद मिलेगी। जब वनों का संरक्षण और प्रबन्ध ग्राम समाज—ग्राम बहुधन्वी संस्था अथवा ग्राम वन श्रमिक समिति—की जिम्मेदारी

हो जायेगी, तो जंगल सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण और सबध में भी परिवर्तन आ जायेगा। उनमें सामूहिक स्वामित्व, स्वर्चि और जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी।

वन्य अधिकारियों तथा वन्य श्रमिक सहकारी समितियों-के प्रतिनिधियों के हवाल ही में सम्पन्न एक सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक प्रमण्डल में चुनिन्दा क्षेत्रों में वन्य कूपों को समितियों को रायल्टी पर सौंपने का प्रयोग किया जाना चाहिये। सरकार को वन्य विभाग और श्रमिकों द्वारा दिये गये अदाजों को ध्यान में रखते हुए तथा समितियों को प्राथमिकता और सहानु-भूतिपूर्ण स्थान देते हुए रायल्टी निश्चित करनी चाहिये।

परस्परावलम्बन की भावना का विकास

चूँकि हम सम्पूर्ण क्षेत्र के साथ-साथ विकास को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, अतः सच्चा सेवा योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि इससे सुगठित एकसम खण्ड के लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उसके साथ ही बाजार निर्मित करने की प्रक्रिया में मजबूती आयेगी। यह प्रक्रिया आदिवासी समुदाय को विकास कार्यों के लिए स्रोतों का उपयोग करने में मदद देगी। और, विकास योजना के जरिये सामाजार्थिक मदों के अन्तर्गत उपबन्ध ही निवेश खर्च की उपयोग-क्षमता को विकसित करने की एक मात्र प्रक्रिया लगती है। चूँकि हम रोजगार योजना के निहितार्थों पर विचार कर रहे हैं, अतः सामाजार्थिक मदों और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की योजना को रोजगार योजना के आधार स्वरूप स्वीकृत करते ही समग्रता और परस्परावलम्बन की भावना विकसित हो जायेगी।

चरागाहों के बरबाद जाने, अर्द्ध-जंगली भूमि और विशेष कर हिरडा वृक्षों और वन्य धन के तेजी से विलुप्ति-करण की गंभीर समस्या को अच्छी तरह हल करना होगा। पिछले बीस वर्षों में वन्य धन पर अधिकांश ध्यान ही नहीं दिया गया है। जब तक इन प्राकृतिक स्रोतों के न्यूनतम संरक्षण की जिम्मेदारी आदिवासी

समाज नहीं लेता, इस रख को पलटा नहीं जा सकता। इस प्रकार सहकारी वन्य प्रबन्ध जैसी कोई व्यवस्था करना अत्यावश्यक है।

औद्योगीकरण की क्षमता

अन्ततः इस क्षेत्र की औद्योगीकरण की क्षमता पर हम विचार करें। प्रचुर घाटी में फल-बागवानी की संभावनाओं का जिक्र पहले ही किया जा चुका है। यह क्षेत्र मुख्यतः धान पैदा करनेवाला है, अतः यहाँ चावल प्रशोधन करनेवाली मिलें निजी क्षेत्र द्वारा पहले से ही स्थापित हैं और सच तो यह है कि वे बड़ी सुस्त चलती हैं। उनकी रोजगारी क्षमता भी नगण्य है। इसके साथ ही प्रायः यह सुझाव दिया जाता है कि हिरडा जैसे जंगली उत्पादनों के उपयोग के लिए छोटी-छोटी प्रशोधन इकाइयों सफलतापूर्वक चलायी जा सकती हैं। सहकारी आधार पर संगठित ये प्रशोधन कार्य आदिवासियों को गैर-मौसम में रोजगारी भी सुनिश्चित करेंगे और आय प्रदान करनेवाली प्रक्रिया का आरम्भ भी। चन्द औद्योगिक इकाइयों आरम्भ करने तथा इन वन्य उत्पादनों की लगातार पूर्ति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न वन्य उत्पादनों के सर्वेक्षण की तत्काल आवश्यकता के लिए विशेष कुछ कहने की आवश्यक नहीं है। इससे लघु इकाइयों में रोजगारी क्षमता का भी पता लगाया जा सकेगा।

हिरडा वृक्ष अकोला तालुके का एक महत्वपूर्ण वन्य उत्पादन है। अभी हिरडा को एकत्रित कर राजूर, कोतूल, शेण्डी जैसे निकटस्थ बाजारों में बेच दिया जाता है, और स्थानीय व्यापारी वर्ग उसे बम्बई और मद्रास भेजता है।

बम्बई प्रान्तीय सहकारी बैंक प्रतिवेदन (१९४७) ने पिछले वर्षों के हिरडा एकत्रण संबंधी आंकड़े दिये हैं। प्रतिवेदन के अन्दाजानुसार १९४० के अन्त तक एक लाख बोरे हिरडा का एकत्रण और निर्यात किया गया। उसके बाद युद्धकाल और युद्धोत्तर काल में जंगलों की बड़े

पैमाने पर कटाई शुरू हुई, जिससे हिरडा एकत्रण में कमी आयी। सन् १९४७ में इस कटाई के कारण एक लाख बोरे हिरडा के बदले सिर्फ तीस हजार बोरे हिरडा की प्राप्ति हुई। यह प्रक्रिया अभी जारी है और अभी करीब दस हजार बोरे हिरडा की प्राप्ति होती। यह हिरडा उत्पादन शोषण का एक अच्छा स्रोत रहा है, क्योंकि खावाती ऋण हिरडा में चुका दिये जाते हैं। हिरडा समितियों के योग्य मचालन से इस शोषण को रोका जा रहा है। कुछ लोगो की यह आशंका है कि अभी इस क्षेत्र में इतनी मात्रा में हिरडा उत्पादन नहीं होता कि उसके प्रशोधन के लिए कारखाने खोले जायें। उसके बदले यह सुझाव दिया जाता है कि अधिक से अधिक परिमाण में हिरडा का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाय।

अनुसंधान योजना

बास रोपण, फल-बागवानी और चाय तथा काफी बागानों— चाय और काफी बोर्ड की मदद से— में चन्द प्रयोग करने से वैसे परिणाम निकल सकते हैं, जिनसे विकास अभिकरण को चन्द औद्योगिक कार्यों की योजना बनाने में, जिससे स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा और स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल हो सकेगा, मदद मिलेगी।

अनुसंधान योजना को हम दो सोपानों में विभाजित कर सकते हैं

स्थानीय लोगो के उपभोग का अध्ययन करने से

टिन का काम, बाल्टी बनाने का काम, किरासन पम्प और किरासन चिमनी निर्माण, पलाश वृक्षों से पत्रावली बनाने, कपड़े की रंगाई और छपाई आदि जैसे चन्द उपभोक्ता सामग्री उद्योग आरम्भ करने की योजना तैयार करने का सुझाव मिल सकता है। इसके लिए पहले स्थानीय बाजार को उचित मुनाफे का आश्वासन और फिर रोजगारी क्षमता का मूल्यांकन आता है। अभी टमाटर उत्पादन, स्थानीय उच्च स्तरीय टमाटर फसल का उपयोग और सहकारी दुग्ध उत्पादन इकाइयों जैसी परियोजनाएँ योजित की जा रही हैं।

वृक्षारोपण

द्वितीय सोपान में वन लगाने की क्रमबद्ध योजना शामिल है। इस जंगली क्षेत्र में तेजी से उगने और धीरे-धीरे उगनेवाले वृक्षों का अनुसंधान करने से नये वन्य उत्पादनों की खोज हो सकेगी।

नरम लकड़ी को कड़ी लकड़ी में बदलने की, जिसकी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत मांग है, प्रक्रियाएँ खोजी जा चुकी हैं।

वैज्ञानिक संरक्षण और वन वृद्धि योजना किसी भी विकास योजना का केन्द्र है और अकोला तालुके जैसे भूतपूर्व घने जंगली क्षेत्रों के लिए तो खास कर। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास की कोई भी योजना बागवानी-सह-वन्य विकास के पक्ष पर जोर देगी।

पंजूर (महाराष्ट्र) १२ अक्टूबर १९६२

पाठकों से

पाठकों से निवेदन है कि खादी ग्रामोद्योग के न मिलने अथवा देर से मिलने के सम्बन्ध में शिकायत भेजते समय वे पते के साथ ही अपनी ग्राहक-संख्या लिखना न भूले। जैसा कि हम चाहते हैं, ग्राहक-संख्या लिखने पर यथा शीघ्र कार्यवाही करने में सहायता मिलती है।

ग्राम्य उद्योगों के विकास के लिए आयोजन

भरियप्पन प. गुरुसामी

किसी खण्ड की विकास योजना बनाने के लिए सर्वेक्षण उद्योग विस्तार अधिकारी द्वारा तीन स्रोतों में किया जाना चाहिये। प्रथम, सभी कारीगर परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण; द्वितीय, द्वितीयक स्रोतों से शक्ति, यातायात की सुविधाओं की उपलब्धि लोक-उपभोग पद्धति आदि के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त करना, और तृतीय, खण्ड की समग्र योजना के साथ ताल-मेल बैठाने के लिए अन्य विस्तार अधिकारियों की योजनाओं के बारे में जानकारी का संग्रह करना।

गुजरात के विकासायुक्त का कहना है कि “हमारे विकास खण्डों की कार्यशीलताओं रूपी श्रृंखला में सम्भवतः सबसे कमजोर कड़ी यह है कि हम ग्रामीण दस्कारियों का विकास करने में असफल रहे हैं—या तो इस कारण कि हम समस्या की तह तक नहीं पहुँच सके हैं या फिर इस कारण कि हमने उस दिशा में दिलोजान से कोशिश नहीं की है। इसलिए हमारे प्रयासों की छाप यह पड़ी है कि वे अव्यवस्थित और अपव्ययपूर्ण हैं। इस कार्यक्रम में इस बात की बड़ी जरूरत है कि गाँवों में दस्कारियों की आवश्यकताओं तथा उनके विकास में आनेवाली बाधाओं को बुद्धिमत्तापूर्वक समझा जाय।” एक तरह से यह वक्तव्य भारत के सभी राज्यों में लागू होता है। अतएव वांछित फल-प्राप्ति के लिए ग्राम्य उद्योगीकरण के कार्यान्वयन में खण्ड स्तर पर काम करनेवाले सभी उद्योग विस्तार अधिकारियों तथा अन्य विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों की जिम्मेदारी अधिक है।

विस्तार अधिकारी के बहुविध कार्य

इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में उद्योग विस्तार अधिकारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें चाहिये कि वे अपने क्षेत्रों में औद्योगिक सम्भाव्यताओं का सर्वेक्षण करें और औद्योगिक विकास योजनाएँ बनायें। औद्योगिक सहकारों

का संगठन करने, कारीगरों को कच्चा माल, बिक्री सुविधाएँ, वित्तीय सहायता और उधार सुविधाएँ प्राप्त करने में आवश्यक सहायता देने, उन्हें उन्नत साधन-संरजाम और उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए तैयार करने, विस्तार सुविधाएँ उपलब्ध करवाने, राज्य उद्योग विभाग, लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के कार्यक्रम कार्यान्वित करने, विचार गोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ आदि आयोजित करने जैसे कामों के अलावा उद्योग विस्तार अधिकारी को अपने क्षेत्र में उपलब्ध अवस्थाओं की समझ प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण और आयोजन का काम भी करना पड़ता है।

सफलता की पूर्व-शर्तें

ग्राम्य उद्योगों का वांछित और सुनिर्देशित ढंग से विकास करने के लिए भी आयोजन का होना आवश्यक है। जैसा कि श्री प सा लोकनाथन् का कहना है, “ग्राम्य उद्योगीकरण भारत का एक सामाजिक लक्ष्य है लेकिन यह बहुत ही शकास्पद बात है कि चाहे जहाँ और प्रत्येक स्थान पर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। उद्योगों की स्थापना से पहले सावधानी पूर्वक यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सफलता की पूर्व-शर्तें मौजूद हैं अथवा नहीं। उत्पादन के लिए बाजार में प्रबल माँग, उद्योग की प्रति लोगों के मन में इच्छा, दिलचस्पी और रुख, कौशल, यातायात और शक्ति तथा अन्य परमावश्यक चीजों की उपलब्धि सफलता की पूर्व-शर्तें हैं।”

ग्रामीण कला और दस्तकारी उद्योग कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जोकि सामान्यतः वैज्ञानिक कृषि और कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योगों के माध्यम से ग्राम्य जीवन की अभिन्न अंग बनी हुई भीषण बेरोजगारी में कमी एवम् उत्पादन में वृद्धि करते हुए समग्र समाज के लिए आर्थिक व सामाजिक प्रगति करने की अवस्थाएँ निमित्त करने का उद्देश्य रखता है, मौजूदा साधन स्रोतों पर आधारित योजना बनाना आवश्यक है। और फिर, उद्योगों का विकास कार्यक्रम खण्ड क्षेत्र की सर्वांगीण विकास योजना का अभिन्न अंग होना चाहिये। उपलब्ध साधन-स्रोतों का यथा सम्भव अधिकतम उपयोग, टालने योग्य बर्बादी से बचने हेतु उपलब्ध साधन-स्रोतों में मितव्ययिता, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अनुकूल-तम उपयोग और निष्क्रिय जन-शक्ति का परिपूर्ण उपयोग आदि सर्वांगीण विकास के मुख्य उद्देश्य समझे जाते हैं।

सर्वेक्षण की आवश्यकता

श्री आर वी राव का कहना है, “भारत जैसे किसी भी देश में किसी योजना का तभी कोई न्यायसंगत महत्व हो सकता है जबकि वह मौजूदा आर्थिक व औद्योगिक विकास से सम्बद्ध हो। इस प्रकार के उद्योगों में लगे व्यक्तियों और यहाँ तक कि समूची आबादी के पेशेवर स्वरूप के सम्बन्ध में भी सही-सही सांख्यिकीय जानकारी का अभाव है। उनकी अवस्था आदि के सम्बन्ध में यथेष्ट जानकारी प्राप्त की जानी चाहिये।”

ग्राम और लघु स्तरीय उद्योगों के लिए योजना बनाने हेतु आवश्यक है कि यह जानकारी इकट्ठी की जाय (क) जन-शक्ति की उपलब्धि, (ख) कौशल और उद्यम की उपलब्धि, (ग) सामग्री, बिजली, जल-पूर्ति, ईंधन, प्रशोधन के लिए कृषिक उत्पादन, संचार सुविधाओं आदि जैसे साधन-स्रोतों की उपलब्धि, और (घ) बाजार की समीपता-रोजमर्रा के काम की विभिन्न चीजों के सम्बन्ध में लोगों की आवश्यकताएँ।

एक अनुभवी उद्योग विस्तार अधिकारी के अनुसार अन्तर्निहित यानी सहज सम्भाव्यताओं के परिपूर्ण

ज्ञान के बिना औद्योगिक विकास के लिए योजनाएँ बनाने का परिणाम होगा परिपूर्ण असफलता। इस प्रकार की असफलता में रुपये-पैसे, समय और श्रम की बर्बादी होगी तथा भावी विकास के लिए असंख्य बाधाएँ खड़ी हो जायेगी। औद्योगिक सम्भाव्यता के मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण में प्रशिक्षण की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। डाक्टर जे सी कुमारप्पा ने एक बार कहा था, “अनुभव से पता चलता है कि आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए जो अनेक नवयुवक आगे आते हैं, वे बिना किसी पूर्व तैयारी के काम के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं।” कुमारप्पा ने यह बात १९४७ में कही थी, लेकिन आज भी वह उतनी ही सत्य है। अनेक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि औद्योगिक सहकारिताओं के सगठन, रियायती दरों पर सरजाम-पूर्ति आदि से सम्बन्धित लक्ष्यों की पूर्ति पर अत्यधिक जोर देने के कारण सर्वेक्षण करने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिल पाता है। यह बात किसी हद तक सही हो सकती है। औद्योगिक शक्त का अन्दाजा लगाने और आयोजन के लिए, सभी जिला तथा राज्य स्तरीय अधिकारी भी अब अधिकाधिक रूप से सर्वेक्षणों का महत्व समझ रहे हैं।

उपयुक्त इकाई

सर्वेक्षण और आयोजन के लिए सामुदायिक विकास खण्ड एक बहुत ही उपयुक्त इकाई हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि २६ औद्योगिक मागदर्शी परियोजनाओं के अनुभव से इस निष्कर्ष को प्रश्रय मिलता है कि लघु उद्योगों के आयोजन के लिए एक जिला अथवा कुछ जिलों का एक समूह आर्थिक दृष्टि से जीव्य इकाई हो सकता है। लेकिन उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का मत है कि खादी, घानी तेल, ईंट पथाई, सिलाई, मधुमक्खी-पालन, ग्रामीण कुम्हारी आदि जैसे ग्रामोद्योगों का खण्ड को इकाई के रूप में लेकर आयोजन किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार खण्ड के औद्योगिक विकास के लिए योजना जिले की योजना के अन्तरंग के रूप में सागोपाग बैठेगी और इसी प्रकार जिले की योजना राज्य की योजना में तथा

राज्य की समूचे देश की औद्योगिक विकास योजना के अन्तरंग स्वरूप सागोपाग बैठेगी। विभिन्न प्रकार की अवस्थाएँ पायी जानेवाले भारत जैसे उप-महाद्वीप में ग्राम्य उद्योगीकरण के लिए हम कोई एक ही पद्धति नहीं रख सकते, नहीं अपना सकते।

उद्देश्य यह नहीं होना चाहिये कि खण्ड के सभी परिवारों का परिपूर्ण सर्वेक्षण किया जाय। घर-घर का सर्वेक्षण करके हम केवल कारीगर परिवारों से ही सांख्यिकीय आकड़े इकट्ठे करते हैं। गाँवों की सामा-जार्थिक अवस्था, साधन-स्रोतों की उपलब्धि, बिजली आदि के सम्बन्ध में विवरण इकट्ठा करने के लिए हमें गाँव के मुखिया, ग्राम सेवक, पचायत तथा अन्य विस्तार अधिकारियों जैसे द्वितीयक स्रोतों के पास उपलब्ध आकड़ों पर निर्भर करना पड़ेगा।

श्रीपेरुम्बुडूर में सर्वेक्षण

यहाँ श्रीपेरुम्बुडूर ग्रामीण उद्योग मार्गदर्शी परियोजना के अनुभव का उदाहरण दिया जा सकता है। श्रीपेरुम्बुडूर परियोजना में पेन्नलुरपेट उप-तालुके सहित श्रीपेरुम्बुडूर और तिरुवल्लूर के दो तालुके हैं। कुल ५२५ गाँव हैं, जो ३०५ पचायतों के अन्तर्गत आते हैं। इन पचायतों के सात पचायत सघ हैं। परियोजना का क्षेत्रफल ६५३ ९७ वर्ग मील और आबादी पाँच लाख से ज्यादा है। दो सांख्यिकीय निरीक्षकों ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर विवरण इकट्ठा किया, जो उद्योग विस्तार अधिकारियों के पास उपलब्ध था। अध्ययन के लिए उन्होंने प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्तियों और पचायत यूनियन काउन्सिल के परामर्श का लाभ उठाया। उन्होंने आबादी, स्थानीय कौशल, मौजूदा उद्योगों, संचार और शक्ति के सम्बन्ध में आकड़े इकट्ठे किये। उन्होंने जनगणना आयुक्त द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अन्तर्गत जिले के कारीगरों के बारे में एकत्रित आकड़ों का सफलता-पूर्वक उपयोग किया।

जब हम सर्वेक्षण करने के तरीके का चुनाव करते तो

हमें समझ लेना चाहिये कि सर्वेक्षण करने के लिए विस्तार अधिकारियों (उद्योग) के सिवाय अन्य व्यक्ति अनुपलब्ध होंगे और खण्ड के सभी परिवारों का परिपूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इसलिए, उपलब्ध स्रोतों से सही आकड़े प्राप्त करने की सीमाएँ समझते हुए हमें तीन सोपानों में सर्वेक्षण करना होगा।

तीन सोपान

सब प्रथम, सभी कारीगर परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहिये। कारीगरों के रहन-सहन की अवस्था और विभिन्न उद्योगों की वस्तु-स्थिति समझने के लिए यह आवश्यक है।

द्वितीय सोपान में गाँव अथवा पचायत के सम्बन्ध में कुछ विवरण द्वितीयक स्रोतों से इकट्ठा करना पड़ेगा। आबादी, शक्ति की उपलब्धि, विभिन्न स्थानों तक जाने-आने, माल भेजने आदि के लिए यातायात सुविधाएँ, सहकारी समितियों के विस्तृत विवरण, कच्ची सामग्री की उपलब्धि, जन उपभोग स्वरूप तथा उपभोक्ता-सामग्री की प्राप्ति के स्रोत से सम्बन्धित जानकारी द्वितीयक स्रोतों के सर्वेक्षण से प्राप्त की जा सकती है। यदि हम खुले दिमाग से स्थानीय बाजारों और मण्डियों का अध्ययन करें तो हम लोगों के स्वभाव और रीति-रिवाजों के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

तृतीय सोपान में अन्य विस्तार अधिकारियों की योजनाओं के सम्बन्ध में आकड़ों का संग्रह करना शामिल है। यदि हम उन्हें सयोजित करें और अपनी योजना को खण्ड की समग्र योजना में फिट बैठे तो ज्यादा विकास होगा। खण्ड में अब तक चलायी गयी योजनाओं, प्राप्त सफलताओं आदि का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा।

जैसा कि श्री आर वी राव कहते हैं, “यदि प्राप्त फल लाभदायक हो, तो लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों के

सम्बन्ध में जाच पड़ताल भीके पर आधारित होनी चाहिये। अनुसंधान कर्त्ता को गाँव या शहर में घर-घर जाना पड़ेगा। यहाँ यह बताया जा सकता है कि लघु स्तरीय तथा कुटीरोद्योग उत्पादक शायद ही हिसाब-किताब रखते हो— रिकार्ड रखने की गुंजाइश तो और भी कम है। अनुसंधान कर्त्ता जो जानकारी हासिल करता है, वह प्रायः मामूली होती है। अतएव, अनुसंधान कर्त्ता को कुटीरोद्योग उत्पादक से प्रश्न पूछने पड़ेंगे, उत्पादन खर्च, बिक्री-मूल्य, बिक्री-व्यवस्था में कठिनाई आदि के बारे में मोटा अन्दाज लगाना पड़ेगा। इसलिए अनुसंधान कर्त्ताओं को यथेष्ट आकड़े प्राप्त करने के काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो उनके लिए यह अच्छा होगा कि वे कुटीरोद्योगी उत्पादक के साथ सहानुभूतिपूर्वक बर्ताब करे तथा यथा— सम्भव सही-सही आकड़े प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर न उठा रखे।”

प्रश्नावली का चयन

सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार करते वक्त हमें चन्द मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिये। प्रश्नावली में बहुत अधिक प्रश्न नहीं होने चाहिये। प्रत्येक प्रश्न सरल और स्पष्ट हो तथा वैसे प्रश्न प्रश्नावली में शामिल न किये जायें जिनसे समुदाय के सदस्यों की भावना को ठेस पहुँचे। सर्वेक्षण कर्त्ता को समझ लेना चाहिये कि प्रश्नावली में किसी प्रश्न को किस उद्देश्य से शामिल किया गया है। प्रश्नों के जो उत्तर प्राप्त हो उन्हें भी स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिये।

विभिन्न अभिकरण भिन्न-भिन्न प्रश्नावलियों का उपयोग करते हैं। उपलब्ध प्रश्नावलियों में से एक का चयन करना उत्तम है। लेकिन जहाँ सर्वेक्षण करना हो उस क्षेत्र में यदि किसी प्रश्न का महत्व नहीं हो तो उसे प्रश्नावली में से निकाल देना चाहिये, तथा यह कि ऐसे प्रश्नों को उसमें शामिल किया जा सकता है, जो और अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

यह स्मरण रखना होगा कि कुछ कारीगर ऐसे हो

सकते हैं जो प्रश्नावली में रिक्त स्थानों की पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसे कारीगरों की संख्या ज्यादा नहीं है जो उक्त काम करने में समर्थ हो। सर्वेक्षण करने के लिए अगर सम्भव हो तो ग्राम सेवकों अथवा विकास खण्ड के अन्य कर्मचारियों का उपयोग किया जा सकता है।

सर्वेक्षण

सर्वेक्षण करते वक्त हमें जानकारी प्रदान करनेवाले व्यक्तियों का मनोविज्ञान समझना होगा। उदाहरण के लिए एक बार एक क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के वक्त वहाँ एक अफवाह फैली हुई थी कि सर्वेक्षण करने के बाद लड़ाई के लिए धनराशि इकट्ठी करने के लिए उक्त सर्वेक्षण किया जा रहा है। इससे लोगों के मन में पूर्वाग्रह पैदा हो गया था। अधिकांश लोगों ने इस प्रकार की जानकारी देने की कोशिश की कि उनके घर का काम ही नहीं चलता है। कभी-कभी उल्टे प्रश्न पूछने से सही उत्तर मिल जाता है। परिवार की कुल आमदनी पूछने की अपेक्षा अगर हम भिन्न-भिन्न स्रोतों से होनेवाली आमदनी के आकड़े इकट्ठी करते जाय तो हमें करीब-करीब सही आकड़े मिल जायेंगे।

अलग-अलग व्यक्तियों ने जो उत्तर दिये उनसे हमें मिलान करके देखना होगा। आय और व्यय सम्बन्धी विवरण प्राप्त करने के पश्चात् खर्च पूरा करने के बाद शेष आय के उपयोग अथवा कमी पूर्ति के ढंग सम्बन्धी प्रश्न पूछने से किसी परिवार की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश पड़ सकता है।

सर्वेक्षण के पश्चात् एकत्रित आकड़ों को संकलित और सारणीबद्ध करना होता है। आकड़े सारणीबद्ध कर लिये जाने पर समूचे खण्ड का चित्र हमारे सामने आ जाता है। सम्बद्ध मदों का प्रातिशत्य निकाला जा सकता है। सारणीबद्ध आकड़ों से मौजूदा अवस्थाओं पर एक विहंगाव-

लोकन हो जाता है।

एकत्रित आकड़ों का विश्लेषण करना सर्वेक्षण और आयोजन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है। आकड़े जिस रूप में इकट्ठे किये गये हों उनका यदि सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया जाय तो वैसे-के-वैसे रूप में समस्याओं पर उनसे कोई प्रकाश नहीं पड़ता, जानकारी नहीं मिलती। उपलब्ध साधन-स्रोतों, मौजूदा औद्योगिक वातावरण और आर्थिक सुविधाओं, उपभोक्ता सामग्री के लिए माग, मौजूदा उद्योगों आदि का हमें विश्लेषण करना होगा। इससे हमें औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी।

आयोजन

ग्राम और लघु उद्योगों को जिन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है वे मोटे तौर पर इस प्रकार हैं रोजगारी प्रदान करना, उपभोक्ता और सरल उत्पादक वस्तुओं की बढ़ती हुई माग का बहुत कुछ हिस्सा पूरा करना तथा कृषि व दीर्घ स्तरीय उद्योगों से निकट रूप से संयोजित एक प्रगतिशील एवम् कुशल विकेन्द्रित विभाग के लिए आधार प्रदान करना।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि सर्वेक्षण और आयोजन तो साधन मात्र हैं। साध्य तो समाज कल्याण है। इसलिए योजना अधिक व्यवहार्य तथा इस प्रकार की हो कि ज्यादा कठिनाइयों का सामना किये बिना लागू की जा सके। अतएव कार्यकर्ता को उपलब्ध वित्तीय स्रोतों तथा ग्राम्य औद्योगीकरण में सहायता देने के लिए चलनेवाले विभिन्न अभिकरणों की योजनाओं की जानकारी होनी चाहिये।

योजना में दो अलग लेकिन परस्पर सम्बद्ध भाग होने चाहिये। प्रथम भाग में मौजूदा उद्योगों और कारी-

गरों को सहायता देने की योजनाएँ हो सकती हैं। ग्रामीण कारीगर को एक अच्छा कारीगर बनाने के लिए हम सभी सम्भव उपायों और साधनों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भाग नये उद्योगों की सम्भाव्यता से सम्बन्धित हो सकता है। ऐसे साधन-स्रोतों पर आधारित उद्योगों को सामने रखना जिनकी खण्ड में विकसित करने की-क्षेत्र में वैसे साधन-स्रोतों का बाहुल्य होने और उनमें से अनेक बेकार जाते रहने के कारण-पर्याप्त गुंजाइश हो। साधन-स्रोतों पर आधारित उद्योगों की सूची देते वक्त इन उद्योगों के उत्पादनों के मागवाले पक्ष का, न केवल खण्ड बल्कि जिला और कभी-कभी तो समूचे देश के सन्दर्भ में, अध्ययन करने का ध्यान रखना पड़ेगा। प्राथमिकताओं का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

चन्द बातों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार ग्राम और लघु स्तरीय उद्योगों के कार्यक्रम की योजना बनाते वक्त उसे मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, लेकिन दोनों श्रेणियों का कार्यान्वयन साथ-साथ हाथ में लिया जा सकता है। उक्त दो श्रेणियाँ हैं (अ) तुरन्त हाथ में लिया जानेवाला कार्यक्रम, और (आ) दीर्घ कालीन कार्यक्रम। योजना विस्तृत रूप में तैयार की जानी चाहिये। योजना में इन बातों का साफ-साफ उल्लेख होना चाहिये चन्द नये उद्योगों की प्रस्तावना का कारण, वित्तीय सहायता की प्रणाली और संगठन का प्रकार। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्रों में अर्जित ज्ञान से योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

कुन्नूर (मद्रास), २९ मई १९६४

मुर्शिदाबाद का सूती और रेशमी खादी उद्योग

कमल बनर्जी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में किस प्रकार रेशम उद्योग में लगे कारीगरों के बीच सूती हाथ-कताई और हाथ-बुनाई लोकप्रिय बनी, इसका बड़ा ही दिलचस्प विवरण इस लेख में है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक जमाने से कुछ सगठित उद्योग चल रहे हैं, परन्तु इनमें रेशम उद्योग को छोड़ कर और कोई भी उद्योग अधिक फैला हुआ नहीं है। रेशम उद्योग ही वह मुख्य अकृषिक उद्योग है, जिसने समय के थपेड़े को सहा है, हाथ करघे पर सूती वस्त्र की बुनाई का काम तो ग्रामीण दस्तकारी के रूप में ही टिक सका है। जिले के कई गाँवों में बहुत-से हाथ करघे थे, जिन पर गरीब ग्रामीणों के लिए चादर, रुमाल और लुगी बुने जाते थे। काडी उप-प्रमण्डल के इन्द्राणी और शेरपुर गाँवों के थोड़े-से सूती वस्त्र-बुनकर मच्छरदानी बुनते थे और आज भी वे दक्ष बुनकर माने जाते हैं। परन्तु आजकल मुर्शिदाबाद जिले में ऐसे कई बुनकर हैं, जिन्होंने सूती खादी बुनाई का काम अपना लिया है, और सूती तथा रेशमी खादी की बुनाई में दक्ष हो गये हैं, जिससे इस जिले के बुनाई उद्योग को एक नयी गति मिली है। रेशम बुनकरो ने सूती खादी बुनाई का काम कैसे अपनाया, यह एक ऐसी कहानी है जिसका सारा श्रेय खादी कार्यकर्त्ताओं को है, जिनकी कर्मठता और सच्चे कार्य ने रेशम बुनकरो को दक्ष खादी बुनकरो में परिणत कर दिया है।

भण्डारों के जरिये बिक्री

गांधीजी ने १९२४ में अखिल भारत खादी मण्डल का गठन किया और भारत के विभिन्न प्रांतों में खादी प्रचार-प्रसार कार्य में लगे रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं ने हाथ-कताई और हाथ-बुनाई के प्रसारार्थ विभिन्न स्थानों में आश्रमों की स्थापना की। इन आश्रमों ने विभिन्न

शहरों व नगरों में अपने बिक्री भण्डार खोले तथा खादी की बिक्री की। तत्कालीन सयुक्त प्रांत के मेरठ शहर में श्री जी भू कृपलानी और अन्य लोगों द्वारा स्थापित गांधी आश्रम के ऐसे कई भण्डार कई शहरों में थे। श्री गांधी आश्रम के बनारस बिक्री भण्डार में मुर्शिदाबादी रेशमी उत्पादनों का स्टॉक रहता था, क्योंकि वे उन्हें हाथ-कता हाथ-बुना वस्त्र मानते थे। मुर्शिदाबादी रेशमी साड़ियों और कपड़े के थान काफी सख्या में इसी भण्डार से बेचे जाते थे। अखिल भारत चरखा सच के भी विभिन्न स्थानों में बिक्री भण्डार थे, परन्तु वह सिद्धान्तत किसी वैसे व्यक्ति से मुर्शिदाबादी रेशमी वस्त्र खरीदने को तैयार नहीं था, जोकि खुद रेशम बुनकर न हो। अतः सच ने रेशम बुनकरो से मीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजने की योजना बनायी और इस निर्णय के अनुसार उसने अपने बिक्री अधीक्षक श्री विट्ठलदास वासनजी जेराजाणी (जो अभी खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य हैं) को १९२५ में, रेशम बुनकरो से सम्पर्क साधने तथा उन बिक्रेताओं को प्रमाणित करने के लिए मुर्शिदाबाद भेजा, जोकि अखिल भारत चरखा सच को रेशमी वस्त्र सप्लाई करे।

श्री जेराजाणी १९२५ में बरहमपुर आये और उन्होंने स्थानीय रेशम व्यापारी (स्व) श्री सुरेन्द्रनाथ सरकार से सम्पर्क स्थापित किया, जिनका रेशम बुनकरो से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। सच का प्रथम प्रमाण-पत्र श्री सुरेन्द्रनाथ सरकार को दिया गया, जिन्होंने अखिल भारत चरखा सच द्वारा संचालित विभिन्न भण्डारों को मुर्शिदाबादी रेशमी वस्त्र सप्लाई करना आरम्भ किया।

बाद में यह मालूम हुआ कि श्री सुरेन्द्रनाथ सरकार भी बिचवानिये थे, क्योंकि वे चक-इस्लामपुर, मिर्जापुर तथा अन्य स्थानों के बुनकरो से रेशमी वस्त्र खरीदा करते थे। इसलिए अखिल भारत चरखा सघ ने चक-इस्लामपुर के श्री रजीत कुमार विश्वास और उनके भाइयों को प्रमाण-पत्र दिया तथा बाद में उसी गाँव के श्री ललित मोहन साहा को १९२६ में प्रमाण-पत्र दिया। रेशम व्यापारियों की ये तीनों फर्म अखिल भारत चरखा सघ द्वारा प्रमाणित मुर्शिदाबादी रेशमी वस्त्र का व्यापार करती थी और श्री विश्वास तथा श्री साहा १९४३ तक, जबकि अखिल भारत चरखा सघ ने रेशम खादी के लिए प्रमाण-पत्र वापस ले लिये, मुर्शिदाबादी रेशम के प्रमाणित व्यापारी रहे।

खादी को लोकप्रिय बनाने के प्रयास

सन् १९३२ में श्री गांधी आश्रम के एक कार्यकर्ता श्री काली चरण शर्मा को आश्रम के बिश्री भण्डारो के लिए मटका रेशम खरीदने हेतु चक-इस्लामपुर भेजा गया। वे खादी-विचार का प्रसार करने आये थे। उन्होंने बुनकरो के इस गाँव में खादी कताई-बुनाई सगठित करने की योजना बनाने के लिए श्री ललित मोहन साहा, श्री रजीत कुमार विश्वास तथा अन्य लोगों से सम्पर्क किया। मटका रेशम खरीदते वक्त श्री शर्मा स्थानीय बुनकरो के सम्पर्क में आये, जहाँ कि चरखा जमाने से प्रचलित था। गांधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन आरम्भ किये जाने के बाद से चक-इस्लामपुर के कई लोग चरखा चलाते थे। कांग्रेसी नेताओं ने लोगों को खादीधारी बनाने के लिए अथक प्रयास किये और स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न गतिविधियों के बावजूद चरखा चलाना नहीं छोड़ा। धीरे-धीरे चक-इस्लामपुर में खादी कताई-बुनाई की जड़े जम गयीं। सन् १९४८ में अखिल भारत चरखा सघ ने प्रमाणित सस्थाओं से सलग्न लोगों के लिए अपने उपभोग हेतु कम से कम ७३ गुड़ी हाथ कथा सूत तैयार करना अनिवार्य बना दिया। उस वक्त चक-इस्लामपुर और बरहमपुर में चार-पाच

प्रमाणित सस्थाएँ थी। चक-इस्लामपुर का उन्मादिनी रेशम कारखाना और चक में उत्पादन करनेवाला बरहमपुर का भारतीय रेशम उद्योग, ये दो अन्य प्रमाणित सस्थाएँ थी, जिन्होंने कि अखिल भारत चरखा सघ द्वारा व्यक्तिगत प्रमाण-पत्र दिया जाना बन्द कर दिये जाने पर अपना कार्य बन्द कर दिया। परन्तु उन सब ने इस जिले में खादी कताई और बुनाई को प्रचलित करने के लिए बहुत कुछ किया।

मुर्शिदाबाद में चक-इस्लामपुर मटका रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और मटका रेशम का बंगाल में तथा बाहर अच्छा बाजार है। इस सदी के पाँचवें दशक में अखिल भारत चरखा सघ और खादी सस्थाएँ बड़ी मात्रा में चक-इस्लामपुर से मटका रेशम खरीदती थी, क्योंकि मटका रेशम परम्परागत खादी मानी जाती थी। सन् १९४३ में अखिल भारत चरखा सघ द्वारा व्यक्तिगत प्रमाण-पत्र की पद्धति बन्द करने का निर्णय लेने के बाद से इस उद्योग के बुरे दिन शुरू हुए। परन्तु उस समय से रेशम बुनकरो ने रेशम और खादी बुनाई का काम स्वयं के तथा अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए अपना लिया। इस प्रकार जो स्थान काफी वर्षों तक मटका रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ चरखा कताई और खादी बुनाई कार्य आरम्भ हुआ। अखिल भारत चरखा सघ द्वारा व्यक्तिगत प्रमाण-पत्रों का बन्द कर दिया जाना परोक्ष रूप से इस जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खादी कताई-बुनाई का प्रसार करने में सहायक हुआ, और उसने रेशम बुनकरो को सूती खादी और रेशमी खादी बुनाई काम अपनाने के लिए मजबूर किया।

स्वतंत्रता के पश्चात्

सन् १९४७ में भारत सरकार ने अखिल भारत चरखा सघ से बड़े पैमाने पर खादी कताई-बुनाई के प्रसार हेतु योजना बनाने के लिए कहा। महात्मा गांधी के दुःख निधन के पश्चात् १९४८ में सेवानाम में सर्वोदयी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व सेवा सघ का गठन हुआ। उक्त

सम्मेलन ने खादी के प्रसारार्थ एक योजना भी स्वीकृत की, जिसे बाद में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। जब डा प्रफुल्ल चन्द्र घोष पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने अभय आश्रम के श्री सत्य रजन सेन को बुलाया और पश्चिम बंगाल के गिरते रेशम उद्योग को पुनः प्राणवान बनाने के कार्यक्रम का भार सम्भालने हेतु उन्हें विशेष रेशम अधिकारी नियुक्त किया। श्री सेन ने एक रेशम शिल्पी सच बीरभूम जिले के बसवा में, दूसरा चक-इस्लामपुर में तथा कुछ और अन्य स्थानों पर गठित करने में सहायता दी। बसवा सच की स्थापना अक्टूबर १९४८ में हुई और उसी वर्ष नवम्बर में चक-इस्लामपुर सच की। श्री नृसिंह प्रसाद विश्वास ने पश्चिम बंगाल के विशेष रेशम अधिकारी की सक्रिय सहायता से सहकारी समिति के तौर पर चक रेशम शिल्पी सच का गठन किया और उस सच को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिली। उसने मालदह जिले में चार लपेटाई (रीलिंग) केन्द्र, मुर्शिदाबाद जिले के चक-इस्लामपुर और मिर्जापुर में चार बुनाई केन्द्र तथा बसवा और सोनामुखी में दो और केन्द्र खोले। बाद में ये रेशम शिल्पी सच प्रमाणित सस्थाएँ हो गयीं। इन सस्थाओं से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत उपभोग हेतु कम से कम ७३ गुडी सूत कातना अनिवार्य था। इसलिए सब ने, बच्चों तक ने, कताई करना आरम्भ कर दिया और धीरे-धीरे इस रेशम बुनाई केन्द्र में तेजी से खादी बुनाई का विकास होने लगा।

महीन सूत कताई

राज्य सरकार के कुटीर उद्योग निर्देशालय के सक्रिय सहयोग के जरिये रेशम उद्योग के पुनरावर्तन से इन सब केन्द्रों के खादी सूतकारों और बुनकारों को भविष्य की एक सुनहरी किरण दिखाई दी। उस वक्त श्री काली चरण शर्मा पश्चिम बंगाल सरकार के कुटीर उद्योग उप-निर्देशक के अतर्गत रेशम बुनकर सगठनों के निरीक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। उनके लिए अधिकाधिक लोगों को खादी क्षेत्र में लाना सम्भव हो सका। सन् १९५२ में मुख्यतः उनके प्रयत्नों से ही बसवा और चक-

इस्लामपुर में कताई मण्डलों की स्थापना की जा सकी, और बसवा में ५०० तथा चक-इस्लामपुर में ७५० चरखे आरम्भ किये गये। बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले में ये दोनों स्थान खादी कार्य के मुख्य केन्द्र बन गये। सन् १९५३ में अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना होने पर इस जिले के सूती और रेशम खादी उद्योग को अधिक गति मिली और स्थानीय सूतकारों ने बंगाल के मूत कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु मलमल बनाने के लिए महीन कताई करना आरम्भ किया।

दक्ष सूतकार

जब से खादी और ग्रामोद्योग कमीशन क्षेत्र में आया है, सूती और रेशमी खादी का उत्पादन करने के लिए कई सस्थाएँ गठित हो गयी हैं। उनमें से कुछ की स्थापना सहकारी समितियों के तौर पर हुई, परन्तु अधिकांश का गठन खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के तत्वावधान में हुआ। इन सभी सस्थाओं ने रेशम उद्योग को पुनः प्राणवान बनाने तथा रेशम बुनकरों को खादी बुनकरों में बदलने हेतु अपनी सारी शक्ति लगायी है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने सर्व प्रथम मालदह में एक रेशम लपेटाई केन्द्र तथा चक-इस्लामपुर में बुनाई-केन्द्र की स्थापना की और उसके बाद शीघ्र ही कमीशन द्वारा छ और सस्थाएँ पंजीकृत तथा प्रमाणित की गयीं। उन सभी सस्थाओं ने इस जिले में सूती और रेशम खादी उद्योग का विकास कार्य अपने हाथ में लिया और दस वर्ष के अन्दर ही ६,००० लपेटक तथा १,३०० बुनकर फिर से अपने पुस्तैनी धंधे में लग गये। उत्तम मुर्शिदाबादी रेशम बनाने के लिए प्रसिद्ध मिर्जापुर और पिथरापुर को भी वही प्रोत्साहन मिला और उद्योग के बुरे दिन धीरे-धीरे समाप्त हो गये।

चक-इस्लामपुर की चन्द्रकाता ललित मोहन रेशम खादी समिति ने एक मलमल कताई स्कूल आरम्भ किया, जिसमें महीन कताई पर जोर दिया गया। इस स्कूल में महीन कताई करना सीखी लड़कियों ने अखिल भारत कताई प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार और

स्वर्ण पदक प्राप्त किये। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन ने इस कताई स्कूल का १९५५ में उद्घाटन किया और महिला प्रशिक्षार्थियों को अपनी कताई में सुधार करने की सलाह दी ताकि वे बढ़िया मलमल के लिए सूत तैयार कर सकें। छ वर्ष के अन्दर इस स्कूल में ३०० से अधिक लड़कियाँ प्रशिक्षित की गयीं और उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय बंगाल तथा अन्य राज्यों में आयोजित कताई प्रतियोगिताओं में दिया। सन् १९५६ में पश्चिम बंगाल राज्य कताई प्रतियोगिता में प्रथम पांच स्थान इसी स्कूल की लड़कियों को प्राप्त हुए। सन् १९५७ में उन्होंने फिर राज्य प्रतियोगिता में प्रथम पांच स्थान प्राप्त किये और बाद में पटना में आयोजित अखिल भारत कताई प्रतियोगिता में भी अच्छी सफलता दिखायी। कुमारी आरती गनई ने महीन कताई में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक पाया और पांच अन्य लड़कियों ने रजत पदक प्राप्त किये। मलमल कताई स्कूल की प्रशिक्षार्थिनियों ने १९५८ में भोपाल में आयोजित अखिल भारत कताई प्रतियोगिता में अच्छा कौशल दिखाया और १९६० में वर्धा में आयोजित अखिल भारत कताई प्रतियोगिता की महीन कताई प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किये। चक-इस्लामपुर की इन लड़कियों की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि इन महीन कताई करनेवालियों के लिए, जो कि किसान और अम्बर चरखे चलाने में भी पटु हैं, मलमल कताई असम्भव नहीं है।

रेशम उद्योग का विकास

रेशम खादी बुनाई के मुख्य केन्द्र हैं चक-इस्लामपुर और मिर्जापुर, परन्तु पिथरापुर, डागापाडा, बिकलनगर, शकरपुर, दादपुर, शक्तिपुर, सोमपाडा, बघरा, रामनगर, पंचथुपी, महिलाहटी और अन्य गाँवों में भी—जहाँ कि रेशम बुनकर अपने पुस्तैनी धड़े में लगे हुए हैं—केन्द्र हैं। यहाँ इस जिले में रेशम खादी उद्योग के विभिन्न विभागों में लगे लोगों की सख्या देना अनुपयुक्त नहीं

होगा। सन् १९०१ में मुर्शिदाबाद में २८,९५० व्यक्ति रेशम खादी उद्योग में लगे थे, सन् १९११ ने उनकी सख्या घट कर २७,३३८ हो गयी और १९५१ में ७२०। कभी अकेले चक-इस्लामपुर में १,२०० हाथ करघे चलते थे, परन्तु १९५१ में खादी और रेशम बुनाई के इस बड़े केन्द्र में सिर्फ ४०० हाथ करघे रेशम बुनाई कर रहे थे। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने स्थापना के बाद कई सस्थाओं को आर्थिक सहायता दी, जिससे रेशम खादी उद्योग में लपेटको और बुनकरो की सख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी। निम्न तालिका में चक-इस्लामपुर में १९५८-५९ में विभिन्न सस्थाओं में कार्य कर रहे लोगों की सख्या दी गयी है, जिससे यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता से सूती और रेशमी खादी उद्योग का विकास हुआ है।

	लपेटक	बुनकर
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन का रेशम केन्द्र	१,१७४	३०३
चन्द्रकांत ललित मोहन रेशम खादी समिति	१,०००	२४०
चक रेशम शिल्पी समवाय सच लि	१,५००	२२३
विश्वास रेशम खादी ग्रामोद्योग कार्यालय	३६८	६२
चक इस्लामपुर केन्द्र बुनकर सहकारी समिति	२१०	७०
अन्य	१,७००	३८०

व्यक्तिगत बुनकर अब सस्थाओं से सम्बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि सस्थाओं के अन्तर्गत काम करना उनके लिए बेहतर है। इस तरह थोड़ी-सी अवधि में चक-इस्लामपुर में लपेटको और बुनकरो की सख्या पन्द्रह गुनी बढ़ गयी है।

खगरा (पश्चिम बंगाल) ७ सितम्बर १९६३

वस्त्र छपाई

दत्तकुमार पै

विभिन्न प्रकार की वस्त्र छपाई की विशेषताओं की, इस लेख में चर्चा की गयी है।

खादी उद्योग में कटाई और बुनाई के उन्नत तरीकों के समावेश ने खादी को अच्छी गति-प्रगति दी है। अब दिनों-दिन खादी के पोत में तेजी से सुधार होता जा रहा है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती लोकप्रियता का अधिक श्रेय खादी की आकर्षक रंगाई और छपाई को है, जिनमें नयी तकनीकों का उपयोग किया जाया है। इस लेख में वस्त्र छपाई के इतिहास और विभिन्न तकनीकों पर प्रकाश डालने का संक्षेप में प्रयास किया गया है।

छपाई क्या है ?

छपाई को सीमित रंगाई कहते हैं। रंगाई में सम्पूर्ण वस्त्र पर रंग चढ़ाया जाता है, परन्तु छपाई में वस्त्र के विशिष्ट भाग पर आवश्यक डिजाइन पर ही रंग चढ़ाया जात है। इस प्रकार कम कीमत पर कलात्मक ढंग की तरह-तरह की डिजाइने प्राप्त हो जाती हैं।

ईसा से इक्कीस सौ वर्ष पूर्व ही मिस्र वासियों ने छपे वस्त्रों का इस्तेमाल किया, जोकि बहुत ही सीमित किस्म की रंगाई थी—वस्त्र छपाई का प्रथम नमूना। हाथ छपाई, सीमित रंगाई, और ठप्पा (ब्लॉक) छपाई का इस्तेमाल कई देशों में आदिकालीन लोगों ने किया। इन्डोनेशिया और जावा के प्राचीन निवासी सीमित छपाई की तकनीक में पूर्ण दक्ष थे। भारत और जावा में बतिक छपाई बहुत ही लोकप्रिय और कलात्मक मानी जाती थी। ठप्पा छपाई तकनीक का उपयोग चीनीयों ने सन् ८०० में किया, जिसकी लोकप्रियता सन् १२०० तक भूमध्यसागरीय क्षेत्र और यूरोप तक पहुँच गयी। ठप्पा छपाई की खोज चीनियों ने की, परन्तु जापानियों ने इसे

स्टेन्सिल छपाई में विकसित किया, जिसे आधुनिक जाली (स्क्रीन) छपाई की जननी कहा जा सकता है।

वस्त्र छपाई को मोटे तौर पर हम चार वर्गों में विभक्त कर सकते हैं— ठप्पा छपाई, बेलन छपाई, स्टेन्सिल छपाई और चार जाली छपाई। इन चार वर्गों की बहुत-सी उप-किस्में हैं जैसे — गाठ रंगाई-छपाई, सीमित छपाई, ताना छपाई आदि।

ठप्पा छपाई

छपाई के सब से पुराने तरीकों में एक, ठप्पा छपाई मूलतः हस्त प्रक्रिया थी। आज यह काम हाथ अथवा मशीन से किया जाता है। कुछ समय के लिये ठप्पा छपाई का प्रचलन बहुत कम हो गया था। परन्तु तेरहवीं और चौदहवीं सदी में जर्मनी में रीनिश भिक्षुओं ने इसका पुनरुद्धार किया। वे इसका उपयोग अपने हस्तलेखों के प्रारम्भिक अक्षरों को सजाने में करते थे। बाद में इसका इस्तेमाल कपड़ों पर होने लगा और इस प्रकार जर्मनी उत्तम और विस्तृत वस्त्र छपाई उत्पादन का केन्द्र बन गया। सन् १७०० में जर्मनी में ऑर्गेबर्ग अपने छपे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ से इसका विस्तार हालैंड, स्पेन, स्वीट्जरलैंड, फ्रान्स और इंग्लैंड में हुआ।

यह छपाई सब से धीमी और सरल है। लकड़ी, लिनोलियम अथवा किसी अन्य धातु पर आवश्यक डिजाइन की कटाई कर लेते हैं। यदि डिजाइन में बहुत ही सूक्ष्म रेखाएँ हों तो उनकी छपाई धातु की पिनी अथवा पट्टियों का इस्तेमाल कर की जाती है। छपाई में इस्तेमाल किये जानेवाले प्रत्येक रंग के लिए अलग-अलग ठप्पे का उपयोग किया जाता है। ठप्पे पर रंग लगा कर कपड़े

की जमीन पर हाथ से उसकी डिजाइन छाप देते हैं।

वस्त्र छपाई के लिए सब से पहला यंत्र सन् १७७० में तैयार किया गया। यह एक प्रेस की तरह था, जिसने ताबे की प्लेटो से छपाई करना सम्भव बनाया। आज इस यंत्र का इस्तेमाल सिर्फ स्वीट्जरलैण्ड में बहुत ही महीन छपाई के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी आकार की डिजाइन को ताबे की प्लेटो में कटाई करके उतार कर ऐसे स्थान पर रख देते हैं, जोकि बेलन के नीचे आता-जाता रहता है।

बेलन छपाई

बड़े ठप्पो के उपयोग ने बड़ी और अधिक डिजाइनों का उपयोग सम्भव बना दिया, जिनमें डिजाइन की बारीकियाँ भी बिल्कुल स्पष्ट उभर आती हैं। पहले इन ताबे की प्लेटो में हाथ से खुदाई की जाती थी, परन्तु सन् १८०३ में विडमर ने ताबीय बेलन पर खुदाई करने के तरीके का उपयोग ताबेय प्लेट पर किया। सन् १८८४ में पेरोटीन छपाई का विकास हुआ। आज भी फ्रांस, जर्मनी और इटली में उसका बहुत उपयोग होता है।

सन् १७८५ में बेल नामक स्काटलैण्डवासी ने इंग्लैण्ड में प्रेस्टन के निकट मॉनसी में प्रथम बेलन छपाई यंत्र का

आविष्कार किया। उसी वर्ष एडम पारकिन्सन ने बेल के यंत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किये, जिससे कई रंगों की छपाई स्पष्ट उठ सके। दो-तीन वर्ष के अनुभव से लीवेसी हारग्रीव, हालै एन्ड कम्पनी ने प्रेस्टन में बेलन पद्धति से वस्त्र पर एक साथ छ रंगी छपाई शुरू कर दी। आज बेलन छपाई पूर्णतः आन्तरिक हो गयी है और आधुनिक यंत्र तो प्रति मिनट दो सौ गज वस्त्र पर सोलह-रंगी छपाई कर सकते हैं।

स्टेन्सिल छपाई

स्टेन्सिल कला के मूल आविष्कारक और उपयोग करनेवाले जापानी थे। इस प्रक्रिया में एक मजबूत कागज अथवा किसी उपयुक्त वस्तु पर डिजाइन काट लेते और प्राकृतिक रंगों में जो डिजाइन रहनेवाली होती है उसे अनकटा छोड़ देते हैं। इस डिजाइन को कपड़े पर रख कर उसके कटे हिस्से में ऊपर से रंग का ब्रश चला देते हैं अथवा रंग छिड़क देते हैं। इस प्रकार स्टेन्सिल छपाई को हस्त प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसके जरिये मूल डिजाइन पदों और रूमाल आदि जैसे वस्त्रों पर उतार सकते हैं। सन् १८९४ में एक स्टेन्सिल यंत्र बनाया गया था और आज भी कहीं-कहीं उसका इस्तेमाल होता है।

बम्बई ४ फरवरी १९६४

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व क्रांतिकारी परिवर्तन की जानकारी के लिए

पढ़िए

जा गृ ति

(साप्ताहिक)

हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित

वार्षिक ६ रुपये

अर्द्ध-वार्षिक ३ रुपये

एक प्रति १२ पैसे

प्रचार निर्देशालय

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन

‘ग्रामोदय’, बम्बई-५६

औद्योगिक सहकारिताएँ और लोकतांत्रिक समाजवाद

त्रिलोक नाथ भास्कर

लेखक ने इस लेख में औद्योगिक सहकारिताओं के कार्य-संचालन के विषय में कई प्रश्न किये हैं और उनमें सुधार के लिए कई सुझाव दिये हैं। उनके द्वारा उठायी गयी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। (१) सहकारी चीनी मिलों में काम करनेवाले बहु-संख्यक कामगारों को मिल के स्वामित्व, प्रबन्ध और लाभ में भागीदारी का अवसर नहीं मिलता, और (२) यदि औद्योगिक इकाइयों जो गाँवों में सगठित किया जाय, तो वे अनुभवशील और प्रतिभाशाली छोटे पूँजीपतियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेंगी। हम प्रस्तुत लेख में उठायी गयी बातों पर पाठकों के विचार आमंत्रित करते हैं। —सम्पादक

पश्चिम में औद्योगिक क्रान्ति ने एक नयी आर्थिक पद्धति का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया—पूँजीदाता और श्रमदाता। यात्रीकरण ने बड़े पूँजी निवेश और स्रोतों के संकेन्द्रण को आवश्यक बना दिया। और, इसने हाथ से काम करनेवाले कारीगरों के औजार छीन पूँजीपतियों को सौंप दिये। पूँजी और यात्रीकरण के उपयोग से उपभोक्ता सामग्रियों का सस्ता उत्पादन सम्भव हो गया। इस प्रकार पूँजीपतियों ने मजदूरों और उपभोक्ताओं दोनों के ही, क्रमशः उनकी रोजगारी में कटौती कर तथा अधिकांश मुनाफा खुद के लिए सुरक्षित कर, शोषण का अवसर पाया। बिचवानियों और थोक व्यापारियों ने भी काफी मुनाफा कमाया। इन थोक व्यापारियों का उपभोक्ता-बाजार और उत्पादकों की इकाइयों पर बड़ा दबाव है, क्योंकि आवश्यक वित्त प्रदान करने के स्रोत उनके हाथों में हैं, जबकि असल में उन्हें कमजोर और दुखी, अधिकार-विहीन तथा दबे हुए लोगों का ध्यान रखना चाहिये। दिल्ली में २९ और ३० नवम्बर तथा १ दिसम्बर १९६३ को सम्पन्न चतुर्थ भारतीय सहकारी कांग्रेस ने सहकार के सभी पहलुओं पर विचार किया, कई रियायतों और अधिकारों की माँग की तथा औद्योगिक सहकारिताओं के विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

भारत में कृषि के बाद रोजगारी का सबसे बड़ा स्रोत

कृषि-उद्योग है। देश-विभाजन के वक्त से ही हम औद्योगिक उत्पादन को सहकारी समितियों के जरिये सगठित करने की बात सोच रहे हैं, परन्तु इस तरह की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त विस्तृत और सघन प्रयास किये ही नहीं गये। प्रथम औद्योगिक कार्यकारी दल ने कई सुझाव दिये थे। स्वीकृत मुख्य सिफारिशों में से कुछ हैं स्वामित्ववाली संस्थाओं का औद्योगिक सहकारिता में परिवर्तन और अभी जो औद्योगिक इकाइयाँ सहकारी आधार पर काम नहीं कर रही हैं उन्हें सहकारी समितियों के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। यदि इस तरह के परिवर्तन की गति काफी तीव्र नहीं रही है तो वह उद्यमी की आशकाओं के कारण जोकि यह पाता है कि मानक उप-नियम और सहकार कानून उसके पैसा लगाने तथा उसकी योग्यता का इस्तेमाल करने के बाद भी समान मताधिकार के जरिये उसे अधिकार-विहीन कर देते हैं। सहकारी समिति का हिस्सा खरीद कर नये सदस्य बननेवाले की तरह ही उसे भी एक ही मत देने का अधिकार रहता है। इससे सारा उत्साह समाप्त हो जाता है। न तो उसके निवेश की सुरक्षा की गारंटी होती है और न ही वह अपने गुणों और जोखिम का बड़ा लाभ ही प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत निवेश के अनुपात में ही देनदारी बंध जाती है। जो व्यक्ति अधिक हिस्से खरीदता है, उसे दूसरों की तरह एक ही मत देने का अधिकार होता है, परन्तु उसकी

देनदारी अधिक होती है। इससे बड़ी बेटब स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बहुत निरुत्साहक भी है क्योंकि उसे बोझ बहन करना होता है, जबकि हिस्सा खरीदनेवाले उसे उनके ढग से काम करने के लिए कह सकते हैं। इन जोखिमों के रहते कोई भी अपने सस्थान को सहकारी समिति में नहीं बदलना चाहेगा।

सच्ची सहकारिता

अधिनियम का पूर्वकथन बहुत स्पष्ट है, “एक समान जरूरतवाले कृषकों और अन्य लोगों के बीच मितव्ययिता, स्वयं-सेवा और परस्पर-सहयोग का विकास करने हेतु सहकारी समितियों के गठन और कार्य-संचालन में सुविधाएँ प्रदान करना। आवश्यक है, ताकि जीवन-स्तर उन्नत हो, व्यापार में वृद्धि हो और उत्पादन की उत्तम विधियों का इस्तेमाल किया जा सके।” क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य होना चाहिये जिनके पास कुछ नहीं है और जिनके पास गुण व कुछ पूँजी भी है उन्हें छोड़ देना चाहिये ?

वे छोटे उद्यमी बन जाते हैं और वस्तुतः सहकारिता के दायरे में नहीं आनेवालों के समर्थक बन जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों का निर्माण करना चाहिये तथा उपनियमों में और यहाँ तक कि अधिनियम में भी, इस तरह की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये जोकि छोटे पूँजीपतियों, गुणी लोगों अथवा कारीगरों को एक-दूसरे पर विश्वास रखते हुए सहयोग करने को प्रेरित करे। औद्योगिक सहकारी संघों विषयक हाल ही में सम्पन्न गोष्ठी में खास शिकायतें थी अच्छे प्रबन्धकों की अनुपलब्धि, वित्त की कमी, कच्चे माल की कमी और बिक्री में कठिनाइयाँ। उपर्युक्त सभी कमियाँ समितियों के सदस्यों में वर्ष के एक बड़े भाग में बेरोजगारी फैलाती है, जिसका अर्थ है सगठन की असफलता। गोष्ठी में एक शोध-लेख में यह बताया गया कि ६१ प्रति शत औद्योगिक समितियाँ अच्छी व्यवस्था में नहीं हैं। इसके विपरीत भारत सरकार की ‘छोटे उद्योगपतियों की सहायता’ योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों को, जिनके पास कुछ निधि भी है

और प्रतिभा भी, समितियों से कहीं अधिक लाभ हो सकता है। औद्योगिक सहकारिता सम्बन्धी गोष्ठी ने एक अखिल भारत औद्योगिक सहकारी संघ के गठन की सिफारिश की है, परन्तु प्रतिनिधियों द्वारा वास्तविक प्रगति तो आपस में ही और अधिक निधि इकट्ठी कर तथा अपने क्षेत्र की ओर छोटे उद्यमियों को आकर्षित करने के उपाय ढूँढ कर ही की जा सकती है। उद्यमियों को उत्पादन कार्य के लिए आकर्षित और प्रोत्साहित करने का सबसे मौजू उदाहरण है सहकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों का गठन। औद्योगिक सहकारी समितियों को इस योजना से विशेष लाभ नहीं हुआ है, ९९ प्रति शत लाभ तो व्यक्तिगत उद्योगपतियों को मिला है।

इस प्रवृत्ति को रोकना है। हमें वातावरण बनाना है और अपनी मदद के लिए एक-दूसरे की मदद करने की उपयोगिता लोगों को समझानी है। सबके कल्याणार्थ सहकारी प्रयास करने के लिए समर्थों और असमर्थों को प्रेरित करने की दिशा में ग्रामदान सच्चा प्रयास है। यह सच्चा सहकार है। यदि इसे सही ढग से समझा जाय तो अच्छे प्रबन्धक, लेखापाल, विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति, बुद्धिजीवी, छोटे पूँजीपति और सरल कार्यकर्ता अपनी तथा लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए एक-दूसरे से सहयोग करेंगे। सहकारी समितियों से सम्बन्धित अधिनियम, उप-नियमों आदि को आम भलाई के सुनियोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करनी चाहिये। राष्ट्रीय सहकारी संघों और राज्यों में स्थित उनकी शाखाओं का मुख्य कार्य जनता को सहकार की शिक्षा देना ही है। उच्चस्थ, राज्य अथवा जिला स्तरीय अन्य संस्थाओं में से कुछ को थोक व्यापारियों का स्थान लेना है।

संघों का काम

सन् १९६३ के अन्त में अमेरिका और यूरोप से कुछ उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक दल भारत आया और वह अखिल भारत निर्माण सगठन की दिल्ली शाखा तथा अन्य सगठनों के प्रतिनिधियों से मिला। यह बताया

गया कि वे सभी थोक व्यापारी थे तथा मौसम और गैर-मौसम में अपने उद्योगों के माल का स्टॉक रखते थे। एव कारखानों में पूरा उत्पादन कराने में सहायक थे। वे खुदरा विक्रेताओं की भी और यहाँ तक कि आयातकों को दीर्घ-कालीन उधार देकर, कभी-कभी तो बारह महीने तक के लिए उधार देकर जोकि माल के प्रकार पर निर्भर है, मदद करते थे।

हमारे सघों और थोक-बिक्री उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को इस अवस्था में आना चाहिये कि वे अमेरिका और यूरोपीय देशों के निजी क्षेत्र के थोक व्यापारियों की तरह का आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। जिस तरह सरकार बड़ी फर्मों का अधिकांश हिस्सा खरीद लेती है, उसी तरह बुद्धिमान उद्यमियों को भी सहकारी समितियों में पूँजी लगाने के लिए भाग प्रशस्त करना वाछनीय होगा। अतः मुख्य आवश्यकता है कर्मों-पूँजी दाता को उचित सुरक्षा प्रदान करने की। यह सहज ही हो सकता है, यदि प्रबन्ध समिति में ३३ प्रतिशत स्थान गैर-कर्म सदस्यों और तकनीकल कार्यकर्त्ताओं के लिए सुनिश्चित कर दिया जाय तथा उन्हें यह अधिकार दे दिया जाय कि प्रबन्ध समिति के जिस निर्णय को वे समिति के लिए हानिकर समझे उसे अमान्य कर दें। इस तरह के निर्णय तब तक कार्यान्वित नहीं किये जाने चाहिये, जब तक कि आम सभा उन्हें स्वीकार न कर ले।

ऋण आदि के रूप में व्यक्तिगत उद्यमियों को तब तक कोई सरकारी सहायता नहीं दी जानी चाहिये, जब तक कि वे औद्योगिक समिति की स्थापना न कर लें अथवा उसमें शामिल न हो जायें। वे औद्योगिक सहकारी समितियों में पूँजी भी लायेंगे और बुद्धि भी। इससे सहकारी समितियाँ मजबूत बनेंगी और सफल हो सकेंगी। अकेली सरकार इन समितियों की मदद नहीं कर सकती। उद्योगपतियों की पहल भी उतनी ही जरूरी है। उन्हें आकर्षित करने के लिए लाभांश की अधिकतम दर सांविधिक ६ प्रतिशत से बढ़ा कर १० अथवा १२

प्रतिशत कर देनी चाहिये, जोकि अन्य उद्योग देते हैं। सबको सहकारी समितियों में अधिकतम पूँजी लगाने का मौका दिया जाना चाहिये। चूँकि गाँवों में सहकारी समितियों आदि में पैसा लगाने के लिए धनी लोगों को कोई खास अभिप्रेरणा नहीं मिलती, अतः वे शहरों में अपनी पूँजी लगाते हैं। सच तो यह है कि वे शहरों में कोई न कोई उद्योग आरम्भ कर देते हैं। यदि उपर्युक्त अवस्थाएँ निर्मित तथा सुविधाएँ प्रदान की जायें तो छोटे-छोटे समर्थ और असमर्थ लोग मिल कर गाँवों में नये उद्योग खड़े करेंगे तथा रोजगारी के अधिक अवसर प्रस्तुत करने एव सेवकों और मालिकों के बीच के भेद को कम करने में मदद देंगे।

सहकार की शिक्षा देना आवश्यक

सहकारी समितियों के सदस्यों को सहकारी जीवन बिताने की शिक्षा देना भी आवश्यक है। सहकारिता के दायरे में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को सहकार के उद्देश्यों और व्यवहार एव उसके मूल्य में परिचित कराया जाना चाहिये। सहकारी समितियों के बहुत कम सदस्य ही स्वयं-सेवा, आत्म-निर्भरता और मितव्ययिता को समझते और अपने जीवन में अपनाते हैं। वे हिस्सा खरीद कर अथवा मजदूरी पर काम कर ही सतोष कर लेते हैं। असल जीवन में वे सहकार का पालन बहुत कम करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री तथा सहकार मंत्री इस आन्दोलन की कमियों को दूर करने के लिए बहुत सचेष्ट हैं। परन्तु वे महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों के सहकारिता अधिनियम को लागू करने से नहीं रोक सके, जोकि सहकारी पंजीयक को बहुत अधिक अधिकार देते हैं।

पंजाब के अधिनियम में पंजीयक की आज्ञा के विरुद्ध अपील करने का उपबन्ध नहीं है। उसमें ऐसे उपबन्ध हैं, जोकि रिश्तेदारों के लिए संयुक्त कारखानेवाली औद्योगिक सहकारी समिति का सदस्य बनना असम्भव बना देते हैं। किसी कारीगर अथवा तकनीशियन को औद्योगिक सहकारी समिति की स्थापना करते वक्त यह देखना होता है कि उसके बेटे, भतीजे आदि जिनकी

इस काम में स्वभावतः रुचि है, दूसरे के साथ समिति के सदस्य बने और समिति द्वारा सभी सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं में हिस्सा बटाये। महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम की धारा ६ की व्याख्या बचत और ऋण समितियों अथवा सेवा सहकरिताओं के लिए अच्छी हो सकती है, परन्तु वह कारीगरों के हित में निश्चय ही नहीं है, क्योंकि वह कारीगर अथवा तकनीशियन के परिवार के कर्म सदस्यों को भी समिति का सदस्य होने से रोकती है। पंजाब के अधिनियम के अनुसार औद्योगिक समिति में कोई गैर-कर्म सदस्य नहीं हो सकता है, जोकि समितियों को पूँजी और कुशाग्रता से वंचित करता है। इन दोषों को दूर किया जाना चाहिये।

ग्रामोद्योग

सहकारी चीनी मिलें वस्तुतः उन किसानों की संयुक्त सम्पत्ति हैं, जोकि पहले अपने गन्ने से अपने ही कोल्हू अथवा भाड़े के कोल्हू से गुड़ तैयार किया करते थे। उनमें से कुछ ने मिल कर मुख्यतः परोक्ष-अपरोक्ष सरकारी आर्थिक सहायता से सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की है। चीनी के असल उत्पादक, कारखाने के कामगारों, को तो मजदूर समझा जाता है, समिति के स्वामित्व, प्रबन्ध और लाभ में भागीदार नहीं। इस तरह की समिति तो औद्योगिक सहकारी समिति हैं ही नहीं। गाँवों से शहरों में जो मजदूर आते हैं वे वहाँ काम न मिलने के कारण हैं। जिनके पास साधन और श्रम है, उनके बीच विश्वासपूर्ण वातावरण बना कर इसे ठीक किया

जा सकता है। फिर, स्थानीय चीजों की खपत के लिए रुचि पैदा करने की भी जरूरत है। हाथ बनी और गृह उद्योग की वस्तुओं को प्रश्रय देने के लिए लोगों में इच्छा पैदा करने के लिए बहुत प्रचार करने की जरूरत है। तेल और कपड़ा तो गाँव में तैयार किया ही जा सकता है। परन्तु सिर्फ उससे ही बेकारी की समस्या का हल नहीं हो सकता। गाँवों में औद्योगिक सहकारों के जरिये अन्य औद्योगिक वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाना चाहिये। यह शहरों की गन्दी बस्तियों की समस्या को भी दूर करने में मदद देगा, क्योंकि यह बिना सोचे-समझे गाँव से शहरों में जानेवाले मजदूरों को रोकेंगा।

उपसंहार

औद्योगिक सहकारों को सफल बनाना चाहिये। अन्य सहकारी समितियों के साथ वे लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव डालेंगे, क्योंकि एकमात्र वही सही दिशा में मानव-समाज को विकास करने के योग्य है। व्यक्ति को स्वेच्छा से अपने को समाज को समर्पित कर देना चाहिये और बदले में समाज को उसके वैयक्तिक विकास और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना चाहिये। निस्सन्देह स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि व्यक्ति आजादी के नाम पर समाज-विरोधी कार्य कर सकता है।

दिल्ली • ५ मई १९६४

खादी ग्रामोद्योग का एकादश वर्षारम्भ अक सितम्बर के अन्त में प्रकाशित होगा। लेखकों से अनुरोध है कि वे अपने लेख सम्पादक के पास यथा शीघ्र भेज दें।

ग्रामीण औद्योगीकरण और भूमि-सुधार

वे. आ. वासुदेवराजू

चूँकि ग्रामीण औद्योगीकरण का उद्देश्य सहकारी कृषि-औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था निर्मित करना है, अतः इसकी सफलता के लिए भूमि सुधार का विशेष महत्व है। वस्तुतः ग्रामीण औद्योगीकरण की नींव तभी ढाली जा सकती है, जबकि भूमि-सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन हो।

ग्रामीण औद्योगीकरण का अर्थ है गाँवों में स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय स्रोतों पर आधारित लघु उद्योगों का सम प्रसार। ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सकल्पित नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी के अवसरों में विविधता, ग्रामीण आय-स्तर में वृद्धि और क्रय-शक्ति का विस्तार लाये जाने की आशा है। ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम की सफलता निर्दिष्ट करनेवाले मुख्य सूचक हैं कच्चे माल की उपलब्धि और तैयार वस्तुओं की स्थानीय बिक्री। ग्रामीण उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति कृषि को करनी है और इसके लिए फसल-पद्धति में परिवर्तन आवश्यक है। कृषि पर जीविकोपार्जन के लिए निर्भर करनेवाली ग्रामीण आबादी को वहाँ उत्पादित माल का उपयोग करने की स्थिति में होना चाहिये। हमारे जैसे देश में, जहाँकि ८२.७ प्रति शत आबादी गाँवों में रहती है, ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन के लिए बाजार गाँवों में ही तैयार करने होंगे।

कृषि से सम्बन्ध

गाँवों में माल की 'वर्तमान माँग,' स्पष्टतः कम आय के कारण, बहुत ही सीमित है। परन्तु 'सम्भावित माँग' तो ग्रामीण आबादी की तरह ही अधिक है। ग्रामीण औद्योगीकरण की बहुत-कुछ सफलता 'सम्भावित क्षमता' को 'प्रभावी क्षमता' में परिवर्तित करने पर निर्भर करती है। वर्तमान अवस्था में इसे किस हद तक और कितने प्रभावी रूप से किया जा सकता है, यह राष्ट्र के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यद्यपि ग्रामीण औद्योगी-

करण का उद्देश्य ग्रामीणों की आय और क्रय-शक्ति बढ़ाना है, तथापि कच्चे माल प्राप्त करने और प्रारम्भिक अवस्थाओं में लोगों को क्रय-शक्ति प्रदान करने, दोनों के लिए ही कृषि के सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था कृषि और उद्योग के बीच एक 'कड़ी' बनाये। इससे ग्रामीण औद्योगीकरण में कृषि की भूमिका प्रकट होती है।

औद्योगिक रूप में विकसित देशों का अनुभव यह रहा है कि जब तक सामन्तवादी प्रथा समाप्त नहीं की जाती, तीव्र औद्योगीकरण असम्भव है। फ्रान्स में तो सामन्तवाद अठारहवीं सदी में ही समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में तो और भी पहले इसे समाप्त कर तीव्र आर्थिक विकास की अवस्थाएँ निर्मित की गयीं। समकालीन इतिहास भी इस नियम की पुष्टि करता है कि सामन्तवाद की समाप्ति के बिना औद्योगिक विकास असम्भव है। भू-स्वामित्व में परिवर्तन करने के कारण चीन और रूस दोनों ने ही अपने औद्योगिक विकास में मार्क की प्रगति की है।

भूमि-सुधारों की आवश्यकता

हमारे देश में अब भी सामान्तवादी प्रथा है और गाँवों में सामन्तवाद के अवशेष को दूर करने में अभी हमें बहुत कुछ करना है। करीब ६० प्रति शत किसानों के पास सिर्फ १५ प्रति शत कृष्ट-भूमि है, जबकि ५ प्रति शत बड़े भू-स्वामियों के पास ४० प्रति शत खेत है। भूमि-सुधार का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके बिना, विशेष कर भारत

जैसे घने बसे देश में, कृषि उत्पादकता में कोई आमूल सुधार नहीं हो सकता। ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए भी भूमि-सुधार उतना ही आवश्यक है, क्योंकि भूमि-सुधार के उद्देश्य अन्ततः आय और लाभ का विस्तार वृहत् ग्रामीण समुदाय में करेंगे, जिससे कि ग्रामीण उद्योगों के उत्पादनों के लिए बाजार निर्मित होगा।

हमारी योजनाएँ इस तथ्य को पूर्णतया स्वीकार करती हैं कि भू-स्वामित्व की असमानताएँ कम करना उन देशों के आर्थिक विकास के लिए, जिनकी कृष्ट-भूमि सीमित है और उस पर निर्भर करनेवाले लोगों की संख्या बड़ी है, अत्यावश्यक योजनाओं में भूमि-सुधार के उद्देश्य इस प्रकार बताये गये हैं पहले से चली आ रही भूमि-व्यवस्था में उत्पादकता बढ़ाने में आनेवाली बाधाओं को दूर करना, कृषि पद्धति के अन्तर्गत शोषण के सभी तत्वों को दूर करना, खेत जोतनेवाले को भूमि के सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और दर्जा सुनिश्चित करना। भूमि-सुधार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित कदम हैं विचवानिये अथवा किरायेवाली पट्टेदारी की समाप्ति, काश्त में सुधार जिसमें किराये में कमी तथा उसका नियन्त्रण भी शामिल है, पट्टेदारी (लीज) के संरक्षण और काश्तकार को स्वामित्व का अधिकार।

जैसे-जैसे भूमि-सुधार के ये क्रमिक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाते हैं, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को वैविध्य प्रदान करना सम्भव होगा। फिर भी, तृतीय योजना स्वयम् ही यह स्वीकार करती है कि भूमि-सुधार का कुल प्रभाव अपेक्षा से कम है। भूमि-सुधार के कार्यान्वयन में कम प्रगति होने के कारण है विकास के सुनिश्चित कार्यक्रम के रूप में भूमि-सुधार को बहुत कम मान्यता प्रदान किया जाना, प्रशासनिक पहलुओं पर अपर्याप्त ध्यान देना, और इस तथ्य को अच्छी तरह महसूस न करना कि सहकारी अर्थ-व्यवस्था निर्मित करने के लिए परभावश्यक नींव है भूमि-पट्टेदारी में सुधार और शीघ्रातिशीघ्र भूमि-सीमा लागू करना।

किराये में कमी करने से काश्तकारों की आर्थिक अवस्था में सुधार होगा। वे अधिक सामग्रियों का उपयोग कर सकेंगे और उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा। इससे ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित दैनिक आवश्यकता की उपभोग सामग्री की बिक्री बढ़ेगी। परन्तु इस दिशा में हुई प्रगति सतोषजनक नहीं है। प्रथम योजना में यह सुझाया गया था कि खेत के कुल उत्पादन का एक-चौथाई अथवा एक-पचमाश भाग से अधिक किराये के रूप में लेने के लिए विशेष कारण दिखाना होगा। द्वितीय योजना में जिनसे के रूप में दिये जानेवाले किराये को नकद में देने के लिए कहा गया ताकि काश्तकारों का बोझ कम हो। अभी भी कई राज्यों में यही पद्धति चालू है कि किराये के रूप में एक-तिहाई अथवा उससे अधिक उत्पादन ले लिया जाता है।

पट्टे का संरक्षण

भू-स्वामी और काश्तकारों के अधिकार-नियन्त्रण सम्बन्धी जटिल-उपबन्धों में पट्टा (लीज) संरक्षण कानून को अप्रभावी बना दिया है। यह कह कर काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया है कि वे 'स्वेच्छा से भूमि-समर्पित' कर रहे हैं। अधिकांश ऐच्छिक भू-समर्पण शकास्पद है। 'ऐच्छिक समर्पण' के पंजीकरण से सम्बन्धित कानूनी और प्रशासनिक कमियों को दूर किया जाना अभी बाकी ही है। द्वितीय योजना में यह प्रस्तावित किया गया था कि जहाँ 'स्वयं खेती करने हेतु' भूमि प्राप्त की जायेगी, वहाँ खुद खेत में काम करना बाध्यकारी होगा अन्यथा बेदखल किये गये काश्तकार को पुनः भूमि-प्राप्ति का अधिकार होना चाहिये। इस सुझाव को राज्यों के अधिनियमों में शामिल नहीं किया गया है। कानून और प्रशासनिक कार्यवाही, दोनों ही सिफारिशों के अनुरूप नहीं रही है। 'निजी खेती', 'व्यक्तिगत श्रम' और 'निजी देखरेख' की जो वर्तमान परिभाषाएँ हैं, उनमें भूमि-सुधार के पट्टा संरक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुधार करने की आवश्यकता है। काश्तकारों

के लिए अनिश्चितता अर्थ-व्यवस्था के विकास के हित में नहीं होगी।

स्वामित्व का अधिकार

भूमि-सुधार का अन्तिम उद्देश्य यथा सम्भव अधिक काश्तकारों को भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। द्वितीय योजना ने भूमिधर-काश्तकार सम्बन्ध के अवशेष को भी समाप्त करने का सुझाव दिया। किस हद तक काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार सौंपा गया है, अभी उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मद्रास जैसे राज्यों में तो अभी तक काश्तकारों के स्वामित्व-अधिकार के विषय में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। सुझाव दिया गया है कि तृतीय योजनावधि में पुनर्गठन न करने योग्य भूमि के काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का कार्यक्रम पूरा करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये। कृष्ण-जोत की सीमा लागू हो जाने के बाद, सीमा से अधिक भूमि रखनेवाले काश्तकारों को सामान्यतया उतनी भूमि का स्वामित्व मिल जायगा, जोकि सीमा से अधिक है। इस विषय में भी विभिन्न राज्यों ने व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तर्गत आनेवाली जमीन अथवा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा मिल कर रखी जानेवाली कुल जमीन की सीमा लागू की है। लेकिन हाल के वर्षों में भूमि-हस्तान्तरण से सीमा सम्बन्धी कानूनों के उद्देश्यों को समाप्त तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर उनके प्रभाव को कम करने की दिशा में प्रश्रय मिला है। परिवार के सदस्यों के बीच कई हस्तान्तरण हुए हैं। सीमा से छूटने भी अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में काफी बाधा पहुँचायी है। सीमा से छूट पाने के लिए धान के खेतों को गन्ने के खेत में बदल दिया गया। वर्तमान कानून की इन कमियों और कमजोरियों के कारण उस अतिरिक्त भूमि में काफी कमी हो जायगी, जिसकी एक समय भूमि-रहित लोगों में वितरण करने के लिए प्राप्त किये जाने की आशा की गयी थी।

भूमि-सुधार कानून के कार्यान्वयन में निम्न कठिनाइयों आती हैं

- १ अधिकारों के सही और आद्यतन रेकार्ड का अभाव,
- २ अधिकार सम्बन्धी रेकार्ड, जिनमें काश्तकारों, उप-काश्तकारों और फमल-बटाइदारों का व्यौरा नहीं है,
- ३ भूमि-सुधार कानूनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में प्रशासनिक तंत्र की असफलताएँ और कमियाँ, विशेष कर ग्रामीण स्तर पर।

इसके साथ ही एक बात यह भी है कि काश्तकारों को कानूनन जो अधिकार मिले हैं, उसकी उन्हें खबर ही नहीं है। इस प्रकार अभी किसी न किसी रूप में सामन्तवादी प्रथा ही चल रही है। काश्त सम्बन्धी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी अभिकरणों द्वारा विशेष रूप से जोरदार और निरन्तर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

योजना आयोग की दुविधा

तृतीय योजना ने भूमि-सुधार कार्यक्रम को शीघ्रता-शीघ्र पूरा करने की अत्यावश्यकता पर जोर दिया है ताकि कार्यान्वयन में देरी होने के कारण पैदा होनेवाली अनिश्चितता की भावना दूर हो जाय। परन्तु योजना आयोग के समक्ष भी अब तक कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। इसकी सिफारिशों पर राज्यों ने पूरी तौर से ध्यान नहीं दिया है। अतः भारत सरकार ने राज्यों से कहा है कि उन्होंने भूमि-सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किस हद तक किया है इसका मूल्यांकन करने तथा यदि आवश्यक हो तो कार्यान्वयन की गति बढ़ाने हेतु सुझाव देने के लिए वे आयोगों की स्थापना करें। राज्यों द्वारा गठित आयोगों द्वारा किये गये अध्ययनों का केन्द्रीय स्तर पर सम्पादन किया जायेगा और उसके आधार पर योजना आयोग की सलाह से भूमि सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सारे देश के लिए एकसम नीति बनायी

जायेगी। इन आयोगों के कार्य और एकसम नीति की रचना पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तथापि, सिफारिशों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों के कंधे पर ही है और किस गति से भूमि-सुधार का कार्य हो रहा है इसका निर्णय इसीसे होगा कि राज्य इस कार्य में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं।

पिछले दशक के अनुभव ने तो अधिनियमों के उप-बन्धों की जटिलता और कार्यान्वय के बोझिल तरीकों को ही प्रकाश में लाया है। भूमि-सुधार सम्बन्धी विचार में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि हमारे देश में फसल-पद्धति और आबहुवा में बहुत भिन्नता पायी जाती है, काश्तकारों की अवस्था सब जगह प्रायः एक-सी ही है। ग्रामीण आबादी को वर्तमान कष्टों से कुछ राहत देने और उत्तम जीवन-स्तर प्रदान करने के लिए भूमि-सुधार की कोशिश की जा रही है। इस प्रयास में शिथिलता मूल उद्देश्यों को नष्ट कर देगी, फिर चाहे विभिन्न राज्यों में वर्तमान अवस्थाओं के आधार पर उसके लिए कितना भी औचित्य क्यों न दिखाया जाय। अतः यह प्रश्न उठाना प्रासंगिक है कि विभिन्न राज्यों के कानूनों में जो मूल परिवर्तन नजर आते हैं, क्या वे वर्तमान

अवस्था में उचित हैं। भूमि-सुधार दो ही प्रकार से प्रभावी हो सकता है ऊपर से (सरकारी प्रयास से) अथवा नीचे से (जन-प्रयास से)। हम समस्याओं का हल मूलतः शान्तिपूर्ण तरीके से करते हैं। फिर भी, अभी क्रांतिकारी परिवर्तन करने की तीव्र आवश्यकता है और इसमें सरकार को बड़ा भाग लेना है।

वैज्ञानिक उपचार

चूँकि ग्रामीण औद्योगीकरण का उद्देश्य है सहकारी कृषि-औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था निर्मित करना, अतः इसकी सफलता के लिए भूमि-सुधार का विशेष महत्व है। ग्रामीण औद्योगीकरण की नींव तभी डाली जा सकती है, जबकि भूमि-सुधार कार्य बृहत् ग्रामीण आबादी को लाभ पहुँचानेवाला ठोस रूप धारण कर ले। तभी ग्रामीण उद्योग अपने उत्पादनों के लिए बढ़ते बाजार की आशा कर सकते हैं। 'प्रभावी माँग' से ही पर्याप्त 'पूर्ति' होगी। माल की पूर्ति करने के प्रयास से ग्रामीण औद्योगीकरण को गति मिलेगी। ग्रामीण औद्योगीकरण के सन्दर्भ में पारिभाषित लक्ष्य की पूर्ति के लिए भूमि-सुधार कार्यक्रम को वैज्ञानिक ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

मदुराई : १९ मार्च १९६४

विभिन्न अवधियों में व्यक्तिगत आय की स्थिति

भित्तात्मक वर्ग (फ्रैमटाइल ग्रुप) (परिवारों का प्रातिशत्य)	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५३-५४ से १९५६-५७ तक			१९६०
					कुल ग्रामीण शहरी		ग्रामीण शहरी	
५५-१००	१४०	१४०	२२०	१७५	२००	१७०	२६०	३१०
१००-१०००	२४०	२३०	३४०	२५०	२८०	२५०	३७०	४२४
१०००-१००००			४१०	...	४४०	४४०	३८०	४५७
१००००-१०००००	७५	८०	९५	८५	८५	९०	७०	४०

स्रोत रिपोर्ट ऑफ दि कमीटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ ऑफ लिबिंग, पार्ट १ (डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ एण्ड कन्सेंट्रेशन ऑफ इकॉनॉमिक पावर)



लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों का सामान्य प्रबन्ध

छोटे-से-छोटे व्यवसाय में भी काम-बन्ध का सुव्यवस्थित सगठन आवश्यक है। लोगो को अपने कर्तव्य का भान होना चाहिये और समय-समय पर होनेवाले परिवर्तनों की उन्हें जानकारी करवाते रहना चाहिये।

हम एक फर्म का उदाहरण ले जिसमें एक सौ व्यक्ति काम करते हैं और दो निर्देशक हैं, जिनमें एक सक्रिय निर्देशक (वर्किंग डायरेक्टर) है। फर्म की अपनी कार्यशाला है जिसमें कुछ मशीनें हैं और दफ्तर कार्यशाला से जुड़ा हुआ है। फर्म में बिक्री प्रबन्धक नहीं है। बिक्री प्रबन्धक का काम एक निर्देशक करता है। अगर फर्म निर्यात व्यापार में खास दिलचस्पी रखती हो तो निर्देशक ही विदेश की यात्रा करता है और एजेन्सियाँ सगठित करने का काम करता है। हो सकता है फर्म में निर्माण प्रबन्धक न हो। एक सीनियर फोरमैन निर्माण कार्य की जिम्मेवारी सम्हालनेवाला हो सकता है। सभी कर्मचारियों से कुछ न कुछ जिम्मेवारी निभाने की अपेक्षा की जाती है।

सगठन के सफल संचालन की जिम्मेदारी सामान्य प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) की है। उसे निर्देशको का सहयोग मिलना चाहिये। व्यवसाय के सभी विभागों के लिए उपयुक्त कर्मचारी प्राप्त करना और उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है। एक छोटी फर्म में निर्देशक पक्ष के अन्तर्गत उप-विभाग नहीं होते। कर्मचारी-गण को अतिरिक्त जिम्मेदारी सम्हालने में समर्थ बनाने के

लिए सामान्य प्रबन्धक द्वारा निर्धारित रोजमर्रा के कामों के अलावा उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना ही चाहिये।

मैं यहाँ एक नयी निर्माण इकाई स्थापित करने का उदाहरण दे सकता हूँ। यह एक छोटी फर्म है जिसकी स्थापना के लिए स्थान प्राप्त किया जाता है। बुनियादी काम निर्धारित किया जाता है। सावधानीपूर्वक तैयार की गयी टिप्पणियाँ कर्मचारियों को प्रदान की जानी चाहिये। अनुवर्ती अनुभव के आधार पर उनमें सशोधन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी टिप्पणियाँ प्रसारित करनी होंगी कि बुनियादी सामग्री का प्रहस्तन करने सम्बन्धी सामग्री भण्डार की कार्य-प्रणाली क्या होगी और मुख्य कारखाने तथा प्रबन्ध कार्यालय से किस प्रकार नयी इकाई का काम सम्बन्धित होगा। कच्ची सामग्री का किस तरह प्रहस्तन किया जाय और किस प्रकार निर्माण के लिए उसे दिया जाय, इस सम्बन्ध में भी टिप्पणियाँ जारी करनी होंगी। निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी कुछ मोटी-मोटी बातें निर्धारित करनी होंगी।

सामान्य प्रबन्ध

सुरक्षा के सम्बन्ध में सामान्य मार्गदर्शन देना आवश्यक हो सकता है। सामान्य प्रशासन मद के अन्तर्गत काम की शर्तें शामिल की जा सकती हैं। टिप्पणियों में काम के घटे, पारिश्रमिक आदि का उल्लेख हो सकता है अर्थात् घटे के हिसाब से अथवा किसी दूसरे रूप में पारिश्रमिक का निर्धारण, कर्मचारी और उनके उत्पादन के सम्बन्ध में

आवश्यक सांख्यिकीय विवरण, परिवहन का उपयोग आदि का निर्धारण।

सबसे पहले हमें यह बात तय करनी होगी कि किस प्रकार के वाहक (कनवेयर्स) का इस्तेमाल किया जायगा, किस प्रकार कर्मचारी वाहक पर बैठेंगे तथा किस प्रकार सामान्यतया वे उन्हें चलायेंगे। वाहक की डिजाइन उन पर जो भार पड़ेगा, जिस गति पर उन्हें चलना होगा और जो उत्पादन जायेगा, उसके हिसाब से बनायी जा सकती है। इसके बाद सामान्य प्रबन्धक और निर्माण फोरमैन को यह विस्तृत रूप में समझाना चाहिये कि नयी व्यवस्था से वे क्या प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं और किस प्रकार यह नयी व्यवस्था कम्पनी तथा जनता दोनों के लिए लाभदायक होगी। वास्तविक संचालन पद्धति के आधार पर कामों में सशोधन किया जा सकता है। हम एक ऐसी छोटी फर्म के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसके पास गूढ़ समय और गति अध्ययन का प्रयोग व विकास करने के लिए सुविधाएँ नहीं हैं।

फुटकर उपभोक्ताओं से आर्डर प्राप्त किये व दिये जाते हैं। इन आर्डरों पर ४८ घंटे के अन्दर कार्यवाही की जा सकती है। सावधानीपूर्वक आयोजन करना आवश्यक है। आर्डर पर कार्यवाही करते वक्त उधार के सवाल पर ध्यान देना होगा। एक छोटी फर्म में इस प्रकार के मामलों की जांच करने का सबसे सतोषप्रद तरीका यह है कि कार्ड सूचीवाला तरीका अखिनयार किया जाय, जिसमें सभी ग्राहकों के विवरण दर्ज किये जा सकते हैं।

खरीद पर नियंत्रण

इस सम्बन्ध में हर किसी को अपने आप से यह सवाल करना चाहिये कि आर्डर फार्म की रूपरेखा कैसी होगी और कितनी प्रतियों की आवश्यकता होगी? आर्डर कैसे भेजा जायगा? बाद में प्रतियों का इस्तेमाल कैसे किया जाना है? यह देखना पड़ेगा कि प्राप्त माल बिल्कुल आवश्यक माल के समान है। सफ़ाई करनेवालों से आनेवाले बीजकों को यह सुनिश्चित करने के लिए

चेक करना पड़ेगा कि उनमें जो रुपया-पैसा दिखाया गया है वह सही-सही रूप में प्रारम्भिक आर्डर की शर्तों के अनुरूप है या नहीं।

एक छोटी फर्म में रुपया-पैसा खर्च करना वास्तव में एक बहुत बड़े रूप में घर का काम चलाने जैसा है। यदि इस मामले में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गयी तो हो सकता है कि उत्पादन पूरा न हो; क्योंकि किन्हीं सघटनों पर रुपया-पैसा अधिक खर्च हो सकता है और हो सकता है कि अन्य आवश्यकताओं पर पहले ध्यान नहीं गया हो तथा उनकी व्यवस्था नहीं की गयी हो।

सामान्य प्रबन्धक

पूर्वानुमान तरीके निर्धारित किये जा सकते हैं। सामान्य प्रबन्धक फर्म की खर्च करने की क्षमता के भीतर रहते हुए अपनी आवश्यकताओं का निर्देश करने हेतु प्रत्येक महीने जिस तरीके का अनुसरण करना है उसका सही-सही रूप तैयार कर सकता है। समस्याओं का विश्लेषण करने, सभी सम्भव तरीकों का विश्लेषण करने और यह देखने की उसमें योग्यता होनी चाहिये कि वे किस प्रकार फिट बैठते हैं। उसे तरीके का निर्धारण करना, मशीनों के संचालन का विशेष ज्ञान होना, ले-आउट और गति क्रम का आयोजन करना तथा मशीनों में संचालन पद्धति निर्धारित करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि किस प्रकार सामग्री अन्दर आती है, कार्यशाला में किस प्रकार उसका प्रहस्तन किया जाता है और किस प्रकार वह बाहर जाती है। वह मशीनी हिसाब-किताब और दफ्तर की मौजूदा कार्य-प्रणाली के साथ उसके संयोजन की योजना भी बना सकता है। उसे संचालन की तकनीकों के बारे में निर्देश देने होंगे।

व्यक्तियों के बीच जो वातावरण निर्मित किया जाता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक छोटी फर्म में कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से बहुत मूल्यवान होते हैं, क्योंकि एक छोटी फर्म में ऐसा शायद ही

होता हो कि एक ही काम को दो आदमी करे।

पिछले वर्षों में प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण चर्चा का विषय बना रहा है। एक बहुत ही मामूली व्यवसाय या कामधधे अथवा उद्योग में भी विकेन्द्रीकरण का महत्व है। अनेक छोटी-छोटी फर्मों में प्रबन्धकीय अकुशलता का कारण है—वहाँ पर उत्तरदायित्व का पर्याप्त रूप में विकेन्द्रीकरण न होना।

है . (१) आयोजन, (२) नियंत्रण, (३) समन्वय और (४) उत्प्रेरणा। यदि उद्योग बड़ा है तो इस उत्तरदायित्व को और आगे विभाजित करने की आवश्यकता है, लेकिन उत्तरदायित्व के व्यवहार में समग्र प्रक्रिया आवश्यक रूप से ही एक सुसंयोजित प्रक्रिया होनी चाहिये।

—पे. बाल कृष्ण मूर्ति

प्रबन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व के चार अंग होते

बिडलापुर (पश्चिम बंगाल) • २० नवम्बर १९६३

खादी और औद्योगिक कानून

वर्तमान श्रम कानून उत्पादन कार्य में सलग्न श्रम और पूँजी के बीच मान्य तथा स्वीकृत अन्त-निहित वर्ग-हित के संघर्ष से पैदा होनेवाली परिस्थिति का सामना करने के लिए बन गये हैं। स्वभावतः इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि उक्त दोनों विरोधी शक्तियों के बीच सतुलन बनाया रखा जाय, और वे किसी न किसी रूप में एक ऐसा समझौता सूत्र पेश करते हैं, जिसमें औद्योगिक शांति कायम रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अथवा पंच फैसले का प्रावधान होता है। अगर हड़त लो अथवा काम के ठप्प पड़ जाने को सफलतापूर्वक टाला जा सके तो इन कानूनों का उद्देश्य कम-ज्यादा रूप में पूरा हो जायेगा। लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस उद्देश्य की पूर्ति होने पर भी इन दो वर्षों के बीच निरन्तर मनमुटाव बना रहता है और वह कभी समाप्त नहीं होता। वर्गों के मध्य समरसता अथवा उद्देश्य की एक्यता स्थापित करने का उद्देश्य रखने के वास्तविक कार्य पर वाञ्छित ध्यान नहीं दिया जाता।

गांधीजी की कल्पना के अनुसार खादी उद्योग को पुनर्स्थापित करने का आधार बिल्कुल अलग ही है। इस उद्योग में किसी भी प्रकार के वर्ग संघर्ष के लिए कोई आधार नहीं है और न ही होना चाहिये, क्योंकि इस उद्योग में श्रमिक के हित के विरुद्ध मालिक के हित जैसी कोई बात नहीं आती। खादी का समग्र सम्बोधन न्यास-

धारिता (ट्रस्टीशिप) के सिद्धान्त पर आधारित है, न कि मुनाफाखोरी के सिद्धान्त पर। जो व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करने के लिए कदम रखते हैं उनसे त्याग करने की और खास कर दलितों और सामान्यतः समाज के लिए न्यासधारियों के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। हो सकता है कि कुछ खादी संस्थाओं के सामने इस उद्देश्य का बिल्कुल स्पष्ट सम्बोधन हो। लेकिन इससे काम का असली स्वरूप ही नहीं बदल जाता।

प्रमाणीकरण के जरिये नियमन

इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए पारिश्रमिक, लाभांश और कीमत को खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की प्रमाण-पत्र समिति, जिसे सर्व सेवा संघ का नैतिक समर्थन भी प्राप्त है, बहुत ही सही रूप में नियंत्रित रखती है। यह न केवल सूतकारों और बुनकरों के लिए निश्चित पारिश्रमिक ही सुनिश्चित करती है, बल्कि खादी काम में लगे कार्यकर्त्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में पारिश्रमिक सम्बन्धी विस्तृत असमानता के लिए भी बहुत कम गुइजाश छोड़ती है, जबकि बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में यह असमानता बहुत ज्यादा पायी जाती है, फिर चाहे वे इकाइयाँ निजी विभाग में हो अथवा सार्वजनिक विभाग में। वस्तुतः श्रमिक कानून जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, वह खादी उद्योग में प्रमाणीकरण नियमों के जरिये पहले से ही विनियमित हो रहा है।

खादी काम को फिलहाल जैसे श्रमिक कानून है उनके कार्यक्षेत्र से अलग रखने के लिए उक्त कथन पर्याप्त होना चाहिये। सम्भवतः यही इरादा कानून बनानेवालों का भी रहा हो। यह इस बात से स्पष्ट है कि औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में किसी भी कानून के बनाते वक्त खादी काम से प्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति अथवा खादी जगत का कोई भी प्रतिनिधि उस काम में शामिल नहीं किया गया और न ही कभी यह आवश्यक समझा गया कि समय-समय पर श्रमिक समस्याओं पर विचार करने के लिए अयोजित सम्मेलनों में सर्वे सेवा सघ या खादी और ग्रामोद्योग कमीशन से किसी प्रतिनिधि को बुलाया जाय। स्पष्टतः खादी जगत को अलग रखा गया है और वैसा करना वस्तुतः मही था।

अस्वस्थ प्रवृत्ति

लेकिन कुछ समय से खादी सस्थाओं और उनके कार्यकर्त्ताओं को भी मनमुटाव और वर्ग सघर्ष के झमेले में घसीट ले जाने की एक प्रवृत्ति दिखायी पड़ रही है। मजे हुए खादी कार्यकर्त्ताओं को अपने खुद के कार्यकर्त्ताओं का 'स्वामी' बताया जाता है। कानूनों के कार्यक्षेत्र का गलत अर्थ लगाकर एक बनावटी दिवाल अथवा बाधा खड़ी की जा रही है, जबकि ये कानून खादी काम के क्षेत्र में भी लागू करने का उद्देश्य शायद कभी नहीं रहा। अपने खुद के हित-साधन में रत और खादी के दर्शन से अनभिज्ञ एक वर्ग के व्यक्तियों की इस प्रवृत्ति को दुर्भाग्यवश कुछ प्रमुख खादी कार्यकर्त्ताओं से भी, सम्भवतः अनजाने में, परोक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला है।

यह सब कुछ ऐसा है कि इससे खादी कार्य और उसके दर्शन की बुनियाद पर ही कुठाराघात होता है, जिसका उद्देश्य 'न्यासधारिता' के सिद्धान्त पर आधारित वर्ग-विहीन सभाज की स्थापना करना है। खादी सस्थाओं को यह भी महसूस करना चाहिये कि इस उद्देश्य से पीछे हटने और छद्म-औद्योगिक नीति को मान्यता देने से निश्चय ही खादी काम में श्रमिक और समवाय विधि (फैक्ट्री लॉ) को लागू करने का आमन्त्रण देना है।

उन्हे यह समझ लेना चाहिये कि खादी कार्यकर्त्ताओं को एक सूत्र में बाधनेवाले प्रेम, विश्वास और सेवा के सामूहिक उद्देश्य के सिवाय कोई दूसरी गति नहीं हो सकती।

इसका अर्थ यह नहीं कि पारस्परिक सम्बन्धों से सम्बन्धित यदि कोई समस्या अथवा उपयुक्त कठिनाई हो तो उसे दूर करने के लिए कोई तन्त्र नहीं होना चाहिये। लेकिन इस प्रकार का तन्त्र खादी कार्य के उद्देश्य और देश में जिस प्रकार का वातावरण यह निर्मित करना चाहता है उसके अनुरूप ही होना चाहिये। यह काम प्रमाण-पत्र समिति का कार्यक्षेत्र विस्तृत करने से सर्वोत्तम रूप में हो सकता है। प्रमाण-पत्र समिति को कार्यकर्त्ताओं के लिए वेतन तथा अन्य सुविधाओं और पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ स्तर निर्धारित करके कामगारों की तरह खादी कार्यकर्त्ताओं एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में समर्थ होना चाहिये।

खादी संस्थाओं की जिम्मेदारी

जहाँ तक समवाय विधि (फैक्ट्री लॉ) का सम्बन्ध है खादी कार्य अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत छोटे-छोटे केन्द्रों के जरिये चलता है। उन चन्द केन्द्रों को छोड़ कर जहाँ अन्तिम प्रशोधन कार्य होता है, कहीं भी कामगारों का जमाव और कारखानों जैसी अवस्था नहीं है। अतएव समवाय विधि का, जहाँ तक वह काम की अवस्थाओं से सम्बद्ध है, खादी केन्द्रों से कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस सम्बन्ध में खादी सस्थाओं पर भी एक जिम्मेदारी है। यदि उन्हे अपनी अपेक्षाओं और आदर्शों पर रहना है तो उन्हे इस सम्बन्ध में परिपूर्ण सतर्क रहना होगा कि चन्द जमाववाले स्थानों में खास कर, और अन्य छोटे केन्द्रों में भी सामान्यतः, काम की अवस्थाएँ ऐसी हो कि वे अन्य औद्योगिक इकाइयों और उत्पादन केन्द्रों के लिए आदर्श बन सकें।

खादी कार्य का विस्तार करने और खादी भावना की रक्षा करने की नीति के अग स्वरूप खादी को औद्योगिक कानूनों के कार्यक्षेत्र से मुक्त करना आवश्यक है। अगर

विश्वविद्यालय, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक विवाद अधिनियमों से मुक्त है, तो कोई कारण नहीं कि खादी भी क्यों न हो, जोकि अपना उत्पादन और बिक्री कार्य करने के बावजूद सामाजिक जीवन पद्धति में परिवर्तन लाने और उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के बदले समरसता पर आधारित उद्योग के रूप में परिवर्तित करने का एक मात्र साधन है। मूक सामाजिक क्रान्ति के विस्तृत सन्दर्भ में खादी समग्र समाज के स्वभाव, सम्बन्ध और औद्योगिक स्वरूप में परिवर्तन लाने का उद्देश्य रखने-वाली सामाजिक शिक्षा में गांधीवादी प्रयोगों का एक माध्यम है।

तथापि, यदि कार्य-साधकता के कारण कोई कानून आवश्यक समझा जाय तो वैसी स्थिति में खादी कार्य

के दर्शन, अनुभव और अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष कानून बनाया जा सकता है। यह बात देश में शिखर के खादी कार्यकर्ताओं पर छोड़ देनी चाहिये कि कौन-सा तत्र परिस्थिति की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम रूप से पूरी कर सकेगा। लेकिन यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि यदि खादी सस्था या उसके अधिकारी को अपने ही कार्यकर्ताओं पर, 'मालिक' शब्द का साधारणतया जो स्वीकृत अर्थ है उस अर्थ में, 'मालिक' की भूमिका अख्तियार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो वैसा करना खादी के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा।

—छोतरमल गोयल

चौमू (राजस्थान) २९ मई १९६४

कृषि में निम्बौरी के गूदे और खली का उपयोग

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अखाद्य तेल और साबुन उद्योग विभाग द्वारा संगठित केन्द्र तेल निकालने के लिए करीब दस हजार टन निम्बौरियाँ वार्षिक रूप से संग्रहित करते हैं। इस परिमाण में वे बीज भी जोड़े जा सकते हैं, जिनका संग्रह स्वतंत्र व्यक्ति करते हैं और जिनके सम्बन्ध में आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

निम्बौरी का गूदा अलग करने से जो गूदा और पेरार्ई करने से जो खली प्राप्त होती है, उसका खेती में लाभदायक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि

- १ इन दोनों में पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं,
- २ मृगफली की खली जैसी अच्छी खाद से यह गूदा और खली सस्ते होते हैं, और
- ३ वे पौधे की कीटों से रक्षा करते हैं।

गूदा

निम्बौरी के गूदे में १२ प्रति शत नेत्रोजन (नाइट्रोजन) और ०.२७ प्रति शत फॉस्फोरिक अम्ल (एसिड) होता है। तेल निकालने से पहले ताजा अथवा सूखी हुई निम्बौरी में गूदा अलग किया जाता है। सूखी

निम्बौरी का गूदा अलग करने से पहले उसे पानी में थोड़ा गलाया जाता है। गूदा उतराने की प्रक्रिया से प्राप्त गूदे और गदले पानी का खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ स्थानों में गूदे को खाद बनाने अथवा जीवाणु (बैक्टीरिया) बढ़ाने के लिए गड़बो में रखा जाता है।

हैदराबाद के नजदीक पट्टनचेरवू में बुद्ध मन्दिर ट्रस्ट ने १९६२ में गदला पानी और सूखा तथा चूर्ण किया हुआ निम्बौरी का गूदा किसानों को बेचा था। इस निम्बौरी के गूदे का भाव उस वक्त छ रुपये प्रति बोरी लगाया गया था। जिन किसानों ने ज्वार की फसल में इसका खाद के रूप में इस्तेमाल किया, उन्हें यह जान कर आश्चर्य हुआ कि जो फसल साधारणतया दूसरे महीने में तीन से चार फुट लम्बी बढ़ती थी, वह उसी समय में आठ फुट तक बढ़ गयी। एक मामले में तो ऐसा हुआ कि पिछले दो वर्ष में पौधों से ज्वार ही पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उस खाद का उपयोग करने पर सात बोरी ज्वार की प्राप्ति हुई। यह उत्पादन उक्त जमीन के औसत उत्पादन से दुगुना था। ऐसा

देखा गया कि ज्वार के लिए धान की भूसी को गूदे के पानी में मिला कर रखने से बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। सब्जी पैदा करने के लिए इस खाद को राख, पोटास और अन्य रासायनिक उर्वरकों के साथ मिला कर उपयोग में लाया जाय तो अच्छी फल-प्राप्ति होती है। उक्त ट्रस्ट ने १९६३ में भी पौंच रुपये प्रति बोरी के हिमाब से १०० बोरी निम्बौरी के गूदे का चूर्ण बेचा।

गूदे का कीट-नाशक के रूप में इस्तेमाल

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया है कि निम्बौरी के गूदे में कीट-नाशक तत्व होते हैं। निम्बौरियों के गूदे के ०.००१ प्रति शत भाग से युक्त विलयन से फसल की टिड्डियों से रक्षा की जा सकती है। इसके अलावा यह छिड़कने पर पौधों की बाढ पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अगस्त १९६२ में टमाटर, प्याज, बन्दगोभी, ककड़ी, तम्बाकू, गेहूँ, गुलाब, अण्डी आम, अनार, नीबू, नारंगी आदि पर उक्त विलयन अर्थात् घोल छिड़क कर सफल प्रयोग किये गये।

नीम का घोल तैयार करते वक्त गूदे का चूर्ण एक कपडे में बाधा जाता है और उसे पौंच मिनट तक पानी में रगड़ा जाता है। इसका अनुपात इस प्रकार होता है कि एक लीटर पानी में एक ग्राम चूर्ण। एक एकड़ जमीन पर घोल छिड़कने के लिए सौ गैलन पानी की जरूरत होगी।

निम्बौरी की खली

वैश्लेषित परिणामों से प्रकट होता है कि निम्बौरी की खली में ५ से ५.२५ प्रति शत तक नेत्रजन होता है। इसके अलावा १.०८ प्रति शत फासफोरिक अम्ल और १.४८ प्रति शत पोटास भी उसमें होता है। नयी दिल्ली स्थित भारतीय कृषिक अनुसंधान संस्था द्वारा किये गये कुछ प्रयोगों से पता चला है कि गन्ने, आलू, कपास और धान की फसलों में निम्बौरी की खली का बतौर खाद के प्रयोग करने से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। संस्था के प्रतिवेदन में कहा गया है

“पूसा की मिट्टी पर इस संस्था में निम्बौरी की खली के साथ जो प्रयोग किये गये उनसे पता चला है कि ७० प्रति शत अण्डी, सरसो और मूंगफली की खली

के नेत्रजन के स्थान पर करीब ६० प्रति शत निम्बौरी की खली का नेत्रजन आठ सप्ताह तक यवक्षारित होता रहा। ऐसा पाया गया कि निम्बौरी की खली में दीमक से रक्षा करनेवाले तत्व होते हैं।”

वास्तविक खाद तत्वों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में कुछ प्रयोग किये गये जहाँ नीम के पेड़ों की भरमार है। फसल पर खाद का क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात निम्न तालिका से प्रकट होती है

प्रायोगिक केन्द्र	फसल	बिना खाद दिये प्राप्त उत्पादन में (पौण्ड में) वृद्धि का प्रातिशत्य
प्रतापगढ़	गन्ना	१३६ ४ १६०० खली
गोरखपुर	„	१० ८-१८ १ १०५ एम
प्रतापगढ़	धान	१९ १ ७५ खली
अलीगढ़	कपास	१५ ४ १०० एन
कानपुर	आलू	१५४ ९ २०० एन

खली का कीट-नाशक के रूप में उपयोग

इस प्रकार निम्बौरी की खली का खाद के रूप में उपयोग करने से फसल की दीमक से रक्षा होती है। ‘फिलो-जिस्टिस सिक्रेला’ नामक कीट नीबू, नारंगी, मोसम्बी आदि जैसे साइट्रस वर्ग के पेड़-पौधों के लिए सबसे घातक होता है। निम्बौरी की खली का घोल अथवा नीम तेल का अर्क (इमलशन) इस कीट के नाश के लिए सबसे अच्छा समझा गया है। घोल तैयार करने के लिए चार औंस खली या नीम तेल के अर्क को एक गैलन पानी में मिलाया जाता है। नारंगी पेड़ के तने पर खली की परत चढ़ाने से उसकी कीटों से रक्षा होती है।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि खली में तेल तत्व ज्यादा न रहे। साधारणतया खली में ११ प्रति शत तेल तत्व होते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर खली में इससे ज्यादा तेल तत्व हो तो उसमें से और तेल निकाल लेना चाहिये।

इसके अतिरिक्त इस बात का भी उपयुक्त ध्यान रखना चाहिये कि किसी फसल में कब, कितनी और कैसे खाद दी जाय। इस सम्बन्ध में स्थानीय कृषिक अधिकारी सहायक हो सकता है।

— अपना सजीव सिकर

बम्बई १७ मार्च १९६४

भारतीय निर्यात व्यापार : तीव्र विस्तार की आवश्यकता*

युवेश चन्द्र शर्मा

हाल ही में स्वतन्त्रतः हुए कई अफ्रो-एशियाई देश अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण में व्यस्त हैं। वे तीव्र आर्थिक विकास करने हेतु बड़े उत्सुक हैं और उनमें से कई ने अलग-अलग अवधियों के लिए विकास कार्यक्रम आरम्भ कर दिये हैं। मजबूत अर्थ-व्यवस्था निर्मित करना बहुत कठिन, जटिल और विशाल कर्म है, विशेष कर कम विकसित देशों में जो घोर गरीबी फैली हुई है उसे देखते हुए। गतिहीन अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाने तथा लोगों की आय बढ़ाने के लिए अभी सबसे जरूरी है तीव्र औद्योगीकरण के जरिये अर्थ-व्यवस्था में विविधता लाना। परन्तु दुर्भाग्यवश सभी कम विकसित देशों में तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक स्रोतों की बड़ी कमी है।

पूँजी निर्माण की धीमी गति

इन देशों में कम आय के कारण पूँजी निर्माण की गति बहुत ही धीमी है और लोगों के पिछड़े होने के कारण देश में आवश्यक तकनीक ज्ञान भी अनुपलब्ध है। वृहत् पूँजी, यंत्रों, तकनीक ज्ञानकारी और कभी-कभी कच्ची सामग्री के लिए भी कम विकसित देशों को विकसित देशों पर निर्भर करना पड़ता है। इस समस्या को सुलझाने का एक रास्ता यह है कि विकासशील देश अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाये ताकि उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। बेशक इसके लिए विकासशील देशों के लोगों को काफी त्याग करना होगा क्योंकि उनका जीवन-स्तर बहुत ही नीचा है, परन्तु

यह इन देशों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए अनिवार्य है।

इस तथ्य के बावजूद कि विकासशील देशों के लिए अपना निर्यात व्यापार बढ़ाना अनिवार्य है, यह काम इतना आसान नहीं है खास कर इसलिए कि निर्यात व्यापार की वर्तमान पद्धति में विकसित देशों का प्रभुत्व अधिक है। यहाँ तक कि प्राथमिक उत्पादनों के मामले में भी विकासशील देशों का हिस्सा, जिन्हें कि वे सामान्यतया निर्यात करने की अवस्था में हैं, मामूली-सा ही है। इसके विपरीत पिछले दिनों औद्योगिक देश प्राथमिक उत्पादनों के विश्व निर्यात में अपना हिस्सा बढ़ाते रहे हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि “उनका हिस्सा १९५० के ४७ प्रति शत से बढ़ कर १९६१ में ५५ प्रति शत हो गया जबकि उसी अवधि में विकासशील देशों का हिस्सा ४१ प्रति शत से कम हो कर २० प्रति शत हो गया (पेट्रोलियम को छोड़ कर)। तथापि, उसी अवधि में प्राथमिक वस्तुओं (कच्चे और अपरिशोधित माल) की व्यापार शर्तें तैयार माल के अनुपात में २६ प्रति शत गिर गयी।”

विकसित देशों के निर्यातक निर्माताओं की कहानी तो और भी दुःखद है। तैयार माल के कुल विश्व निर्यात में उनका हिस्सा तो करीब ६ प्रति शत ही है। निकट भविष्य में इस अवस्था में किसी विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि विकसित देश अपना निर्यात बढ़ा तथा आयात कम कर अपनी अर्थ-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए

* दि जर्नल ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड, वर्ष १५, अंक ५ (ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स नम्बर), मई १९६४, वाणिज्य प्रचार

निर्देशालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली, पृष्ठ ७५३-९८८, मूल्य : एक रुपया।

चितित है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विकसित राष्ट्रों का यह रख अपनी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा व्यापक आधार देने हेतु विकासशील देशों के प्रयासों में बाधा पहुँचा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

अब सर्वत्र यह मान्यता है कि विकासशील देशों को अपने पैरों पर खड़ा होने के प्रयासों में समर्थ बनाने के लिए विकसित देशों को भी समान हिस्सा बटाना चाहिये, और विकसित देशों की तरह ही विकासशील देशों को भी अवसर की समानता प्राप्त हो, इसके लिए विशेष उपाय करने हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के वर्तमान रख को उलट दिया जाय ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार की प्रक्रिया को विकासशील देशों के पक्ष में करने में गति लायी जा सके।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई उपाय सुझाये गये हैं। एक है टैरिफ में कमी तथा उसे बन्द कर देना और बाधाओं एवं प्रतिबंधों को दूर करना जिससे ऐसा उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो सके कि उसमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियाँ मुक्त रूप से भाग ले सकें “ताकि विभिन्न देशों के बाजारों में कम विकसित देशों के सभी उत्पादनों को मुक्त और पूर्ण स्थान प्राप्त हो सके।” सिर्फ यही नहीं, यह भी सुझाया जाता है कि “विकासशील राष्ट्रों के निर्यात को बिना किसी भेद-भाव के प्रश्रय दिया जाना चाहिये।” यह विशेषतया इसलिए आवश्यक है कि विकासशील देशों के पास अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करने के लिए पर्याप्त आन्तरिक व्यवस्था (इन्फ्रा स्ट्रक्चर) नहीं है और कम विकसित देशों में निर्माण का खर्च भी विकसित देशों से अधिक पड़ता है।

भारत ने भी इस बात का समर्थन किया है कि “प्रत्येक सामग्री के लिए ‘व्यापार विकास घटाव-बढ़ाव निधि’ खोल कर आर्थिक क्षतिपूर्ति पद्धति के जरिये विकासशील देशों के प्राथमिक उत्पादनों के

लिए उचित और अच्छी कीमत मिल सके, इसके लिए उपाय निकालने चाहिये।” विकासशील देशों की आय बढ़ाने के साथ ही साथ उन देशों में उपलब्ध मानवीय कौशल का पूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए निर्यातों में वैविध्यीकरण परमावश्यक है। यह उनके तीव्र औद्योगीकरण तथा उनके उद्योगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त कर ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

शीघ्रातिशीघ्र उक्त आधार पर कार्यवाही करने की आवश्यकता दिनोदिन अधिक महसूस की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन, केनेडी राउंड वार्ता आदि इस दिशा में प्रत्यक्ष सूचक हैं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक उपायों के निरर्थक होने के बावजूद, जिनका इस शताब्दी के चौथे दशक में सर्वनाशी अनुभव हुआ, विभिन्न राष्ट्रों ने इन प्रतिबंधों में कोई ढिलाई की हो, ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि इसके विपरीत ही लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि विकसित राष्ट्र अपनी समृद्धि को अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, विकासशील देशों को उसमें हिस्सा बटाने नहीं देते और यूरोपीय साझा बाजार आदि जैसे क्षेत्रीय व्यापार सगठनों में प्रवेश कर उनके आर्थिक मार्गों को बन्द कर रहे हैं। तथापि, आशा की जाती है कि विकसित राष्ट्र इस परिवर्तन की हवा को -यान में रखेंगे तथा अपने कमजोर भागीदारों की मदद को आगे आयेगे ताकि ससार की समृद्धि में उन्हें उचित अंश मिल सके। प्रश्न है कि वे इसे कितनी जल्दी करते हैं।

विदेशी सहायता

निर्यात विस्तार के अलावा विकासशील देशों में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने का एक जरिया विदेशी सहायता है। कई विकसित देशों ने विभिन्न विकासशील राष्ट्रों की कई योजनाओं के अन्तर्गत सहायता की है। परन्तु दुर्भाग्यवश सहायता प्रायः घरेलू उद्योगों के निर्यात बाजार की खोज की दृष्टि से दी जाती है और फलतः

वह विशिष्ट परियोजनाओं अथवा देशों से बंध जाती है। स्वभावतः इस सहायता से विकासशील देशों को जो लाभ होनेवाला है, वह बहुत कुछ इन अनुबन्धों के कारण समाप्त हो जाता है। भारत ने आग्रह किया है कि “यदि दी गयी सहायता को विकसित राष्ट्रों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली होना है, तो इसे न तो परियोजनाओं से ही और न ही देशों से बनना चाहिये, बल्कि यह सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध होनी चाहिये।” और आदात राष्ट्र को किसी भी राष्ट्र से ऋण करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। इसी प्रकार “ऋण चुकाने की अवधि लम्बी होनी चाहिये ताकि जिस उद्योग अथवा परियोजना के लिए सहायता दी जा रही है उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के बदले उस देश को पर्याप्त निर्यात क्षमता बनाने का समय मिल सके। ब्याज की दर भी उचित होनी चाहिए।”

निर्यात में वृद्धि

विकासशील राष्ट्र होने के नाते भारत भी अपना निर्यात व्यापार जितना बढ़ा सकता है उतना बढ़ाना चाहता है। भूतकाल में देश को निर्यात के प्रति सजग बनाने और निर्यात विकास के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु कई कदम उठाये गये हैं। यह सतोष की बात है कि इन प्रयासों में पर्याप्त सफलता मिली है। कुल निर्यात मूल्य १९६१-६२ के ६ अरब ८० करोड़ रुपये से बढ़ कर १९६२-६३ में ७ अरब १४ करोड़ हो गया। वर्ष १९६३-६४ में उसमें ८१ करोड़ रुपये की और वृद्धि हुई। इतना निर्यात पहले कभी नहीं हुआ था। निर्यात मूल्य में वृद्धि कुछ हद तक कुछ किस्म के माल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई परन्तु अधिकांश निर्यात में वृद्धि के कारण ही हुई। “वर्ष १९६३-६४ में निर्यात वृद्धि में एक अच्छी बात यह है कि कई वस्तुओं का तथा कई देशों को निर्यात हुआ।”

वर्ष १९६३-६४ में वृद्धि दर्शानेवाली मुख्य वस्तुएँ हैं चीनी, जूट के तैयार माल, नये तैयार माल, वनस्पति तेल,

तम्बाकू, कमायी और परिशोधित खाले, नकली रेशम की तैयार वस्तुएँ आदि। ‘नये तैयार माल,’ कमायी और परिशोधित खाले तथा नकली रेशम की तैयार वस्तुएँ आदि के अन्तर्गत निर्यात में जो वृद्धि हुई है, उसका विशेष स्वागत है और यह हमारी अर्थ-व्यवस्था के विविधीकरण का निश्चित सूचक है। तथापि, १९६३-६४ में भी हमारे निर्यात किये जानेवाले माल में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादन ही थे। कुल निर्यात में उनका हिस्सा ५० प्रति शत से अधिक था, जबकि तैयार माल का प्रातिशत्य करीब ३३ था। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश को औद्योगिक बनाने में अभी और बहुत कुछ करना है ताकि निर्यात में प्रशोधित और तैयार माल का अनुपात अधिक हो सके। एक दूसरी विशेष बात यह है कि प्रथम बार अपरिष्कृत चीनी का निर्यात किया गया और उसका स्तर सतोषजनक था।

जहाँ तक निर्यात-दिशा का सम्बन्ध है, १९६३-६४ में सबसे अधिक वृद्धि (४ करोड़ ७० लाख रुपये) एशियायी और ओसीनियायी देशों को किये गये निर्यात में हुई। अमेरिका को किये गये निर्यात में करीब १० करोड़ ५० लाख रुपये की वृद्धि हुई। पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी करीब उतने की ही वृद्धि हुई। पूर्वी यूरोपीय देशों के मामले में कुल वृद्धि कुछ अधिक थी— १२ करोड़ रुपये। दुर्भाग्य-वश अफ्रीकी देशों के निर्यात में तीन करोड़ रुपये की कमी हुई। चाय और अत्यावश्यक तेल आदि के मामले में निर्यात में कमी हुई।

गारण्टी निगम

निर्यात विस्तार का भारतीय कार्यक्रम बहुत बड़ा है और आशा है कि १९७० तक निर्यात दूना हो जायेगा—करीब १५ अरब रुपये। स्वभावतः इससे सेवा सुविधाओं के विस्तार की भी आवश्यकता होगी। इस दिशा में निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना ने निश्चय ही एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति की है और भारतीय निर्यातकों की जोखिम दूर करने के लिए अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध

की है। वर्ष १९६३-६४ के दौरान बीमा निगम ने २९ करोड़ ४५ लाख रुपये की जोखिम उठायी। इसने एक बहुत ही उपयोगी पुस्तकालय और सूचना केन्द्र खोला है, जिसमें १५ हजार विदेशी ग्राहकों के नाम दर्ज हैं। निर्यात जोखिम बीमा निगम को पूर्ण विकसित निर्यात, साख और गारंटी निगम में परिवर्तित करने का भारत सरकार का निर्णय निश्चय ही निर्यात विकास में अधिक सहायक होगा, क्योंकि जोखिम उठाने के अलावा, वह बैंकों को कई तरह की गारंटी भी देता है ताकि निर्यातकों को ब्याज की अनुकूल दर पर आवश्यक ऋण सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। आशा है कि निर्यात, ऋण और गारंटी निगम भारत में भी उतना ही लोकप्रिय हो जायगा जितने कि इस तरह के निगम पश्चिम यूरोपीय देशों अथवा जापान में लोकप्रिय हैं।

व्यापार विस्तार अंक

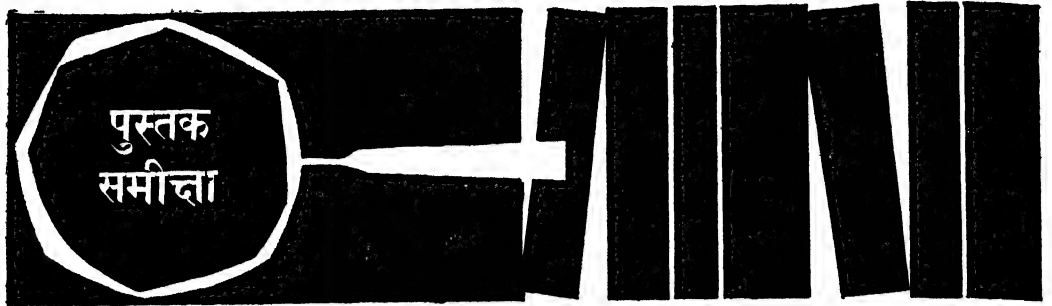
आलोच्य अंक में १९६३-६४ में भारतीय निर्यात व्यापार और उसी वर्ष के लिए निर्यात, ऋण और गारंटी निगम की कार्यशीलताओं की समीक्षा देने के अलावा विदेशों में भारत के जो व्यावसायिक सचिव/कौंसल/व्यापार आयुक्त आदि हैं, उनके द्वारा लिखे गये २७ लेख प्रकाशित किये गये हैं, जिनमें उन्होंने उन देशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात के विषय में लिखा है। इन लेखों में सम्बन्धित देशों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति की विशेषताओं पर, विशेष कर भारतीय निर्यात और उसके और विस्तार की सम्भावनाओं के सन्दर्भ में, पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कई देशों में तेजी से बदलती राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाओं की दृष्टि से भारतीय निर्यातकों को इन लेखों में जो सकेत तथा विभिन्न देशों की आवश्यकता के अनुरूप माल के सम्बन्ध में जो विस्तृत

मार्गदर्शन दिया गया है, वह भारतीय निर्यातकों के लिए बड़े व्यावहारिक लाभ के होंगे। उसी प्रकार व्यापार विस्तार अंक में दी गयी जानकारी से वाणिज्यशास्त्र के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा।

परन्तु यह जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस अंक में जिन २७ देशों के विषय में लिखा गया है, उनमें से ११ एशियायी और ओसीनियायी हैं एवम् छ पूर्वी यूरोप के, पाँच पश्चिमी यूरोप के, तीन अफ्रीका के तथा दो अमेरिका के। एशियाई देशों को जो महत्व दिया गया है वह सर्वथा उचित है परन्तु इस विशेषांक में अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के विषय में, जहाँ हमारी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की सम्भावनाएँ ज्यादा हैं विशेष कर तैयार माल की, अधिक जानकारी दी जानी चाहिये थी।

जेनेवा में २५ मार्च १९६४ को सम्पन्न राष्ट्र सघीय सम्मेलन के मन्त्रिपरिषद् अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री मनुभाई शाह ने सम्मेलन के कार्य की व्याख्या करते हुए विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं को बताया तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र की वर्तमान अनियमित अवस्था में सुधार लाने के निश्चित सुझाव दिये, ताकि विकासशील राष्ट्र गरीबी और भुखमरी को दूर करने एवम् अपनी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने में निश्चित और प्रभावशाली कार्य कर सकें। उक्त भाषण को इस विशेषांक में शामिल कर इसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी गयी है।

बम्बई २२ जून १९६४



स्टडीज इन इण्डियन फॉकलोर (लोक-गीत, लोक-कला और लोक-साहित्य), शंकर सेन गुप्त और के.डी. उपाध्याय द्वारा सम्पादित, इण्डियन पब्लिकेशन्स, कलकत्ता-१, १९६४, पृष्ठ सख्या सोलह+१८९ मूल्य ५ रुपये।

संकट काल में जब कोई देश वर्तमान अवस्थाओं को अपर्याप्त और असह्य पाता है, तो वह अपने इतिहास एवम् लोक-राग (फॉकलोर) की ओर मुड़ता है, जो वस्तुतः इतिहास का ही दूसरा रूप है। अनेक देशों में हम पाते हैं कि राष्ट्रीय परिवर्तन की अवस्था में वहाँ लोक-राग और लोक-संस्कृति के प्रति पुनः अभिरुचि जागृत हुई। सोवियत संघ और नाजी जर्मनी के उदाहरण हमारे सामने हैं, जहाँ लोक-राग और लोक-गीतों पर पर्याप्त बल दिया गया। चीनी साम्यवादियों ने तो जन साधारण को साम्यवादी आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए तैयार करने में लोक-राग और लोक-कला का विभिन्न रूपों में व्यापक उपयोग किया। हमारे देश में शास्त्रों को लोकप्रिय बनाने और लोक-रागों के संग्रह की ओर सर्व प्रथम ध्यान उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के साथ दिया गया। अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीयों ने जब विदेशी प्रभुत्व के तिरस्कार और तत्कालीन सामाजिक एवम् आर्थिक व्यवस्था की गुरुगम्भीर त्रुटियों को समझ लिया, तो प्रेरणा के लिए पश्चिम के आधुनिक विचारकों के साथ-साथ देश के अतीत के गौरव की ओर भी वे प्रवृत्त हुए। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, जिन दिनों बंगाली अधिकाधिक संख्या में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे, तो साथ ही साथ वे संस्कृत

से ऋग्वेद (रमेशचन्द्र दत्त द्वारा बंगला में अनूदित, जिन्होंने सुप्रसिद्ध इक्नॉमिक् हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भी लिखी), महाभारत (कालीप्रसन्न सिन्हा द्वारा अनूदित) तथा अन्य शास्त्रों का बंगला अनुवाद भी करते रहे। सामान्यतः भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रादुर्भाव के साथ ही समस्त राज्यों व भाषावार क्षेत्रों में इतिहास तथा संस्कृति के प्रति, जिसमें लोक-संस्कृति भी थी, नयी अभिरुचि विकसित होने लगी। बीसवीं सदी का प्रारम्भ-होते-होते स्वातन्त्र्य-आन्दोलन की गति तीव्र हो गयी और उसके साथ ही साथ अतीत के इतिहास और लोक-राग के प्रति रुचि की गहनता भी बढ़ती गयी। आज भारत फिर एक चौराहे पर खड़ा है, और देश में उपस्थित पंचमेल तत्वों को निखार कर एक नया राष्ट्र निर्मित करने के संघर्ष में रत है। और, मजे की बात यह है कि साथ ही लोक-राग के प्रति भी नयी अभिरुचि जागृत हो रही है। प्रस्तुत प्रकाशन उसी अभिरुचि का प्रमाण है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद नयी-नयी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने देश के विभिन्न भागों में लोक-संस्कृति को प्रकाश में लाने और पुनः प्राणवान बनाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया। उद्योग और हस्त-शिल्प के क्षेत्र में हो रहे विकास का भी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है। लोक-गीत, लोक-कला और लोक-राग भी इससे अछूते नहीं रहे। भारत के विभिन्न भागों के लोक कलाकार अब अनेक अवसरों पर दिल्ली में एकत्रित होते और अपनी कला तथा संगीत का प्रदर्शन करते हैं। परम्परागत ग्राम उद्योगों और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने की राजकीय नीति का भी इस सबंध में

लाभकारी प्रभाव पड़ा है। उदाहरणार्थ, खादी को बढ़ावा देने की नीति से तनजेब और शाल बनाने की गौरवशाली परम्परागत कला को जीवित रखने में मदद मिली है।

आलोच्य प्रकाशन के प्रथम भाग में अपनी प्रस्तावना में श्री शंकर सेन गुप्त, ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों द्वारा लोक-रागों के विभिन्न रूपों में उपयोग किये जाने से रूष्ट है। उनका तर्क समझ में नहीं आता। भारत जैसे ग्राम-प्रधान देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को लोकप्रिय बनाने के लिए यदि लोक-राग का सहारा नहीं लिया जाय, तो यह कार्य अत्यन्त कठिन होगा। श्री सेन गुप्त को प्रचार-प्रसार के लिए भी लोक-राग और लोक-गीत के उपयोग पर आपत्ति है। इस आपत्ति को भी स्वीकार करना कठिन है। क्या यह तथ्य नहीं है कि अनेक प्राचीन लोक-गीत और लोक-राग वस्तुतः किसी विचार अथवा वृत्तान्त की अभिव्यक्ति के लिए ही रचे गये थे। सन् १९४२ के दिनों में, जब मैं पूर्वी बंगाल के एक गाँव के स्कूल का विद्यार्थी था, मैंने अनेक लोक-गायकों को ऐसे लोक-गीत गाते सुना, जिनमें न केवल गाँव अथवा आस-पास के जिले में घटित सामयिक घटनाओं का, बल्कि प्रान्त और यहाँ तक कि विदेशों के घटना-चक्रों का भी वर्णन होता था। मुझे आज भी याद है कि उन दिनों के एक सर्वाधिक लोकप्रिय गीत का कथानक था मैंमनसिंह में सम्प्रदायवादियों द्वारा एक नव विवाहित युवक की हत्या। एक दूसरा गीत चेतारवनी के रूप में था, जिसमें भविष्य-वाणी की गयी थी कि १९४२ में सत्तार में प्रलय हो जायेगा। लोग अधिकाधिक संख्या में गायकों को घेर कर उनके गीतों का रसास्वादन किया करते थे। मेरे विचार से यदि समसामयिक हलचलों को लेकर गीतों की रचना की जाय तो उन पर बड़ी सजीव चर्चा होगी।

समय और अभिरुचि के परिवर्तन के साथ लोक-राग, लोक-गीत तथा लोक-कला की विषय-वस्तु बदलती रहती है और संस्कृति ने होनेवाले परिवर्तनों का जिस हद तक उस लोक-राग में समावेश होता है, उसी हद तक वे

अपनी जीव्यता और लोकप्रियता बनाये रखते हैं।

भौगोलिक स्थिति का भी लोक-राग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, बंगाल के तटवर्ती भागों के लोक-गीत, लोक-राग तथा लोक-कला अन्य क्षेत्रों से बहुत भिन्न हैं।

कोई गीत, लोक-गीत है अथवा नहीं इसका निर्णय उसके आशय अथवा उद्देश्य पर उतना निर्भर नहीं करता, जितना कि उसकी भाषा और सरगम के सहज गुणों पर।

इण्डियन फॉकलोर सोसायटी और उसकी मासिक पत्रिका **फॉकलोर** भारतीय लोक-रागों का विभिन्न सांस्कृतिक तथा भाषात्मक रूपों में सुव्यवस्थित अध्ययन करने की दिशा में प्रशसनीय कार्य कर रही हैं। प्रस्तुत प्रकाशन में अपने क्षेत्र के जाने-माने विद्वानों की लोक-राग (फॉकलोर) के विभिन्न पक्षों पर सत्तरह रचनाएँ हैं। इसके साथ ही डाक्टर के डी उपाध्याय द्वारा लिखित ज्ञानवर्द्धक सामान्य सम्पादकीय है, जिन्होंने **फॉकलोर** के सम्पादक श्री शंकर सेन गुप्त के सहयोग से आलोच्य प्रकाशन का सम्पादन किया है। लोक-राग सम्बन्धी साहित्य में यह एक विनिष्ट योग है।

पुस्तक की छपाई-सफाई सुन्दर है और उसके आकार, विषय-वस्तु तथा गुण-स्तर को देखते हुए उसका मूल्य बहुत ही उपयुक्त है।

बम्बई: २८ जून १९६४

—सुभाष चन्द्र सरकार

दि प्रोमोशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट इन करल एरियाज इन इण्डिया; इण्टरनेशनल लेबर ऑफिस, नयी दिल्ली, १९६४।

एशियाई देशों में रोजगारी विकास की समस्याओं पर विचार करते हुए सन् १९६२ के अन्त में मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के पंचम क्षेत्रीय सम्मेलन ने सुझाव दिया था कि रोजगारी के अधिक अवसर निमित्त करने के लिए योजना इस प्रकार की होनी चाहिये जोकि आर्थिक विकास को सुनिश्चित

करे। ग्रामीणों को लाभदायक रोजगारी प्रदान करने हेतु आर्थिक नीति को व्यापक कार्यक्रम पर विशेष जोर देना चाहिये। गाँवों की बेकारी और अर्ध-बेकारी की समस्या का सर्वोत्तम हल ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम है, जोकि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को विविध बनाने में भी सहायक होगा। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार गृह उद्योगों में १ करोड़ २० लाख लोग लगे थे, जबकि निर्माण उद्योगों में ८० लाख लोग ही लगे थे।

यद्यपि बहुत-से लोग यह समझते हैं कि सिर्फ ग्रामोद्योगों और दस्तकारियों की स्थापना से ग्रामीण औद्योगीकरण का विकास हो सकता है, जबकि वस्तुतः ग्रामीण औद्योगीकरण के विचार को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। तेजी से बदल रही परिस्थितियों में ग्रामीण और शहरी उद्योगों के बीच का भेद अब रक्षणीय नहीं है। परन्तु इतना तो ध्यान में रखना चाहिये कि अकेले गाँव के लिए नये उद्योग का स्व-संचालन कठिन है। कई गाँव मिल कर ही यह कार्य कर सकते हैं।

रोजगारी के अवसर विकसित करने के साधन हेतु ग्रामीण औद्योगीकरण का अर्थ महज गाँवों में यहाँ-वहाँ चन्द कारखाने अथवा सयत्र स्थापित कर देना नहीं है। उन्हें वैसे स्थानों और अवस्थाओं में स्थापित करना चाहिये कि वे गाँवों की सर्वोत्तम सेवा कर सकें। परमावश्यक चीजें हैं आधुनिक तकनालाजी को गाँवों में लाना और यह सिर्फ शहरों के जरिये ही किया जा सकता है, जोकि प्रशिक्षण, परिवहन, संचार, बाजार, विद्युतशक्ति, तकनीकल और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए सस्थाओं सम्बन्धी सुविधाएँ आदि प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। परन्तु तकनालाजी को एक ही बार में गाँवों में नहीं ले जाया जा सकता। प्रारम्भिक अवस्थाओं में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर धीमे-धीमे प्रभाव डालने का प्रयास किया जाना चाहिये, जिसके फलस्वरूप रोजगारी के अवसर बढ़ें। ऐसा वातावरण बनाना है, जोकि लोगों को प्राविधिक प्रगति के लाभ बतायेगा।

इस सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शी आयोजन दल

के विचार विशेष उल्लेखनीय हैं, जोकि उसने जुलाई १९६३ में भारत सरकार को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में व्यक्त किये। दल ने स्पष्टतः यह कहा था कि औद्योगिक विकास के विकेन्द्रीकरण हेतु बृहत्तर नगरों और गाँवों पर ध्यान न दिया जाकर इन दोनों छोरों के बीच के शहरों और कस्बों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। दल ने यह भी कहा कि छोटे-छोटे योग्य कारखानों का भविष्य उज्ज्वल है। आद्यतन तकनीकों और औजारों का इस्तेमाल करनेवाले छोटे-छोटे कारखाने ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं और वे ग्रामीण-विभाग के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

ग्रामीण औद्योगीकरण को ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रोजगारी के अवसर निर्मित करने की व्यापक योजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिये। ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम में शहर अथवा नगर में केन्द्र रूप में काम करनेवाले बड़े उद्योग तथा उसके साथ ही आस-पास के गाँवों में सेवा करनेवाले लघु उद्योगों को भी उतना ही स्थान मिलना चाहिये, जितना कि ग्रामीण और कुटीरोद्योगों के पुनर्स्थापन और विकास को। लघु उद्योगों की श्रेणी में आनेवाली औद्योगिक इकाइयाँ बड़ी औद्योगिक इकाइयों की शाखाओं के रूप में काम कर सकती हैं। अतः कृषि, दस्तकारियों, ग्रामीण, लघु और बड़े उद्योगों एवं सेवाओं के समग्र और समन्वित विकास की दिशा में प्रयास करना चाहिये। इसके लिए कच्चे माल और कारीगरों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और कुटीर उद्योग की रचना और सम्भावना को उपयुक्त रूप में विस्तृत करना है। यह काम इन उद्योगों को शामिल कर किया जा सकता है बिस्कुट, केश-तल, साबुन, बढईगीरी, लोहे के बर्तन, शीच के बर्तन, तैयार कपड़े, कृषि-सुरजाम और छोटे यंत्र, हाथ के औजार, साइकिल के पुर्जे, पेट, वार्निश, फलों और तरकारियों की पैकिंग, कैनिंग और आरक्षण, जैम, जेली और चटनी बनाने तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के उत्पादन आदि।

बम्बई : १४ जुलाई १९६४

—जगदीश नारायण वर्मा

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए 'ग्रामोद्योग' इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५९ से प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल. एसोसिएटेड एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ५०५ तारदेव, आर्थर रोड, बम्बई-२४। वार्षिक शुल्क २ ५० रुपये, एक प्रति २५ पैसे।

भारतीय भाषाओं' के दैनिकेतर पत्रों में, वार्षिक पत्रों के अलावा, खादी ग्रामोद्योग को १९६३ में श्रेष्ठ छपाई और सजावट के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुद्रण और आकल्पन राजपुरस्कार का यह नवम वर्ष है।

दशम वर्ष • सितम्बर १९६४ • द्वादश अंक



	पृष्ठ
बढते मूल्य	—उत्तरंगराय न. ठेबल ७७१
इजरायल मे कृषि-उद्योग समन्वय	—वैकुण्ठ ल. मेहता ७७५
खादी और ग्रामोद्योगो के लिए संगठनात्मक स्वरूप	—अक्षय कुमार करण ७७८
कछार का सामाजार्थिक सर्वेक्षण	—सुहास चटर्जी ७८२
आर्थिक प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था मे	
औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था	—मुहम्मद मोहश्वीन ७८५
ग्रामीण उद्योग और लोकतांत्रिक समाजवाद	—वेकटेशन् पन्ननामन ७९०
विभिन्न ग्रामोद्योगो का सापेक्षिक महत्व	—देवेन्द्र कुमार गुप्त ७९४
टीका-टिप्पणी	
सहकारी प्रशासन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	—एन. वाय. खेर ७९६
गोबर गैस सयत्र : एक अध्ययन	—जशभाई झ पटेल ७९७
उत्तर प्रदेश मे गुड के सग्रह की समस्याएँ	—भारत भूषण कंशाल ७९९
जम्मू और कश्मीर का पशुधन : चन्द समस्याएँ	—माखन लाल मट ८०२
मद्रास के एक गाँव का आर्थिक चित्र	—त. शो. यशवंत और ने. सु. तिरुवेक्काचारी ८१०
दक्षिण कॅनरा मे बदलौन व्यापार	—नवीनचन्द्र कृ. तिगलाया ८१३
भ्रष्टाचार निवारण के लिए उपाय	८१६
अखाद्य तेल से विकेंद्रित साबुन उत्पादन	—सुभाष चन्द्र सरकार ८२६
पुस्तक समीक्षा	८३१
दि ट्रायबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन ऍन ऑटोबायग्राफी	
इवोल्यूशन ऑफ पचायती राज, लेखक : आर वी जठार	
पाठको के विचार	८३४
विषय सूची १९६३-६४	क से प

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोदय', इर्ला, बम्बई-५६ से मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थशास्त्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ सहर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ (ए एस) के पते पर भेजें। टेलीफोन नं ५७१३२९।

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति : २५ पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिये - असिस्टेण्ट एकाउण्ट्स ऑफिसर (कैश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ (ए एस)

इस अंक के लेखक

उछरगराय नवलशकर ढेबर	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष ।
वैकुण्ठ लल्लूभाई मेहता	—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।
अक्षय कुमार करण	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के सदस्य-सचिव ।
सुहास चटर्जी	—सिलचर (असम) स्थित कछार कालेज में इतिहास विभाग के अध्यक्ष ।
मुहम्मद मोहसीन	—अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) स्थित मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में लेक्चरर ।
वेकटेशन् पद्मनाभन	—मद्रास स्थित मद्रास राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सचिव ।
देवेन्द्र कुमार गुप्त	—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य, इन्दौर (मध्य प्रदेश) ।
एन बाय खेर	—पूना स्थित कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेण्टर के प्राचार्य ।
जशभाई झवेरभाई पटेल	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की गोबर गैस योजना के निर्देशक ।
भारत भूषण कसाल	—गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित एच एम एच कालेज में वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष ।
माखन लाल भट	—वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) स्थित कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र में प्रवर अनुसंधान सहायक ।
तडलम सोमसुन्दर यशवत	—मद्रास विश्वविद्यालय के कृषि-अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र में प्रवर अनुसंधान-कर्त्ता ।
नेदुमरम् सुन्दरराजअय्यंगर तिरुवेकटाचारी	—मद्रास विश्वविद्यालय के कृषि-अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र में अवर अनुसंधान-कर्त्ता ।
नवीनचन्द्र कृष्णप्पा तिगलाया	—बम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में अनुसंधान सहायक ।
सुभाष चन्द्र सरकार	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित खादीग्रामोद्योग और जागृति के सम्पादक ।

बढ़ते मूल्य

छछरंगराय न. देबर

कीमतों में वृद्धि अस्वाभाविक है और वह महान चिन्ता का विषय बन रही है। स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रस्तुत लेख में चन्द सुझाव पेश किये गये हैं।

आज की ज्वलत समस्या है बढ़ते मूल्य। दो प्रमुख कांग्रेस सदस्यों ने यह कहा बताया कि लोगों को वर्तमान मूल्य वृद्धि योजित विकास के सामान्य परिणाम-स्वरूप स्वीकार करनी चाहिये और कठिनाइयों को राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में सहना चाहिये। मैं उनसे तथा उन लोगों से, जोकि वैसे ही विचार रखते हैं, नम्रतापूर्वक यह कहना चाहूँगा कि वे कतई गलत हैं, क्योंकि देश में पहले से ही अपार दुख और विपदा व्याप्त है, जोकि मूल्यों में असामान्य वृद्धि से और भी तीव्र हो गये हैं।

अस्वाभाविक वृद्धि

मूल्य वृद्धि की मात्रा बहुत बड़ी है। जनवरी १९६३ में थोक विक्री मूल्य सूचकांक १०८.७ था। जनवरी १९६४ में यह १२० था। जून १९६३ में थोक विक्री मूल्य सूचकांक १२२.३ था और जून १९६४ में १३५.६। सबसे अधिक वृद्धि अनाज के मूल्य में पायी जाती है। मई १९६३ में गेहूँ का मूल्य सूचकांक ८७.८ था, और मई १९६४ में वह सूचकांक ११३.६ था अर्थात् २० प्रति शत से अधिक वृद्धि हुई। जून १९६३ में वह ९१ या ९२ था और जून १९६४ में ११७। मोटे अनाज के मामले में भी जनवरी से मई १९६३ के बीच जो सूचकांक ११० और १२८ के बीच झूलता था, वह जनवरी से मई १९६४ में बढ़ कर १२३ से १५० हो गया।

विकास खर्च, बढ़ती आबादी, शहरीकरण और आबादी के एक वर्ग की आय में वृद्धि मूल्यों को बढ़ाते हैं। परन्तु उपर्युक्त आकड़ों के अनुसार तीव्र

मूल्य वृद्धि की व्याख्या सिर्फ़ उनसे ही नहीं की जा सकती। इसके और भी गहरे कारण हैं और यह समझना आवश्यक है कि उनसे अधिक खतरा है। सन् १९६४ जनता और सरकार के लिए गम्भीर चेतावनी का वर्ष है।

राजनीतिक-वित्तीय-प्रशासनिक कारण

इन बढ़ते मूल्यों के कारणों की खोज—जिनकी वजह से अपार दुख फैल गया है, अमलमजदूरी में बहुत कमी आ गयी है और सब जगह चिन्ता व्याप्त हो गयी है—राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक स्तरों पर नीतियों और कार्यान्वयन के क्षेत्र में करनी है।

नीति-स्तर पर कृषि विभाग की बहुत बड़ी उपेक्षा की गयी है। गम्भीरतापूर्वक विचार न कर लापरवाही से विचार किया गया है, मौखिक सेवा की गयी है और लगातार प्रयोग किये गये हैं। यह प्रक्रिया १९५०-५१ में आरम्भ हुई। वर्ष १९५०-५१ में केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय का सिद्ध उपाय था अमेरिका से बड़े पैमाने पर अनाज का आयात—अकाल रोकने के लिए नहीं, बल्कि सदा मौजूद रहनेवाली कमी को दूर करने के लिए नियमित कार्य के रूप में। स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई ने, जोकि बाद में खाद्य मंत्री बने, विभागीय आकड़ों को एक ओर रख दिया और, अपने पूर्वाधिकारी द्वारा पेश किये गये आर्डर तथा अनुकूल बारिश की मदद से, नियंत्रण हटा कर ठीक ही किया। दुर्भाग्यवश उनके दुःखद निधन के बाद कृषि विकास, विशेषकर अन्न उत्पादन के क्षेत्र में, के लिए यथार्थ नीति नहीं अपनायी रखी जा सकी। इसके विपरीत श्री

किदवाई ने जो विश्वास पैदा कर दिया उससे, उनकी मृत्यु के बाद, नेताओं ने यह समझना शुरू कर दिया कि समस्या का हल हो चुका है और यहाँ तक कि द्वितीय योजना के उद्देश्यों में कृषि का करीब-करीब कोई नाम ही नहीं था।

थी किदवाई के निधन के बाद केन्द्रीय खाद्य मन्त्रालय कई व्यक्तियों के हाथोंसे होकर गुजर चुका है और भिन्न प्रकारकी नीतियों का पालन कर चुका है जिनमेंसे प्रमुख हैं अन्नस्वावलम्बन, अनाज का राजकीय व्यापार अन्न नीति का अन्तिम उद्देश्य राज्य व्यापार, अनाज व्यापार का सहकारीकरण, वक्त-जरूरत के लिए स्टॉक रखना, पी एल ४८० पद्धति, विभागीय पद्धति, राज्यवार सम्भाग, कंट्रोल नहीं और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। यह सब मिबाय प्रयोग के और कुछ नहीं था। सरकार हमेशा एक ही दल के हाथ में थी। मंत्री बदल जाने से नीति भी बदल गयी। इतने महत्वपूर्ण मामले में इस तरह की अकुशलता के कारण देश को दण्ड का भागी होना पड़ा है।

तीन अत्यावश्यकताएँ

जब तक कृषि के बुनियादी महत्व के निहिनार्थ को पूरी तौरसे और उद्देश्यात्मक विश्वास के साथ कार्यान्वित नहीं किया जाता, तब तक सब ओर अनिश्चितता, असतोष और बढ़ते मूल्य की वर्तमान अवस्था में कोई महत्वपूर्ण गुधार नहीं हो सकता। पर्याप्त उत्पादन, मुनिश्चित पूर्ति और आर्थिक अनुशासन, ये तीन चीजें आर्थिक आयोजन के लिए उतनी ही अत्यावश्यक हैं जितनी कि उपयुक्त तकनीके वित्तीय स्रोत और ऊठोर परिश्रम। प्रथम तीनों में से हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। जिम हृद तक हम इन पर ध्यान देंगे, उस हृद तक कीमतें कम होंगी।

अ पर्याप्त उत्पादन

जहाँ तक पर्याप्त उत्पादन का सवाल है, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बौद्धिक प्रयासों की कमी कभी भी नहीं रही है। तथापि, कार्यान्वयन हमेशा पीछे रहा है।

इसके तीन कारण हैं विभागों के उचित वितरण पर पर्याप्त ध्यान न देना, सरकारी तंत्र की अयोग्यता और उत्पादकों को अच्छी तरह सोच-समझ कर दिये जानेवाले प्रोत्साहन का अभाव। भूमि-सुधार का प्रभावी कार्यान्वयन करने में बचा नहीं जा सकता। इसी तरह तृतीय और चतुर्थ योजना के लिए क्रमशः ९ करोड़ टन और १२ करोड़ टन निश्चित खाद्यान्न लक्ष्य निर्धारित करना है, मन्त्रालय की जिम्मेदारी पर बजन डालना है, किसानों को अच्छी कीमत देनी है।

आ मुनिश्चित पूर्ति

मुनिश्चित पूर्ति हमारी अत्यावश्यकता है। यह काम वैज्ञानिक हाट-व्यवस्था का है। यह सम्पूर्णतः सरकारी अथवा मिश्रित अथवा गैर-सरकारी हो सकती है। परन्तु इसका संगठन वैज्ञानिक ढंग से ही होना चाहिये। देश के आकार और निजी व्यापार तथा प्रशासनिक सेवाओं की सीमा का ध्यान रखते हुये अर्थात् तर्कसंगत आधार पर मार्ग प्रशस्त करना है। उत्पादन, ऋण और विक्री को इस तरह एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिये कि विक्री के लिए बचा हुआ अतिरिक्त माल गलत लोगों को न बेच दिया जाय। वितरण-पद्धति की कमी इस तथ्य से विल्कुल सामने आ गयी है कि देश के एक भाग में स्टॉक रहने पर भी दूसरे भाग के बाजारों में मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उसे ठीक समय पर बेचना सम्भव नहीं हुआ है।

इ आर्थिक अनुशासन

तीसरी चीज है उचित वित्तीय प्रबन्ध। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था आर्थिक आयोजन के प्रतिकूल नहीं है, परन्तु मिश्रित अनुशासन की बात तो सोची ही नहीं जा सकती। सफल विकासशील देशों के विकासकालीन अनुभवों का हमने कोई लाभ नहीं उठाया है।

१ सादगी

हमने सादगी को एक वाग्गी गृह कर दिया है। समृद्ध पश्चिम की स्पर्धा करने के जोश में हमने हजारों वर्षों

की परम्परागत राष्ट्रीय जीवन-पद्धति, जिसमें आवश्यकताओं पर नियंत्रण करने पर बल दिया जाता है, को छोड़ समय से पूर्व ही आधिक्यवाली अर्थ-व्यवस्था के मूल्यों की प्रतिष्ठा करने की कोशिश की।

२ गुप्त धन

हम गुप्त धन की शिकायत करते हैं। यह हुआ कैसे? स्वर्गीय डा. जान मथाई जैसे मध्यमार्गी और उदार विचारवाले व्यक्ति ने भी वस्त्रोद्योग जाच समिति के प्रतिवेदन में 'आय' पर सीमा बाधने का सुझाव दिया था। हम उस प्रतिवेदन को मानने से इकार करते हैं। हम यह समझते हैं कि सामन्तशाही नियंत्रण से कर की चारी, सट्टा बाजार, काली रकम और घुसखोरी को रोक सकेंगे। हर चेतावनी के बाद यह सम्भव नहीं हो सका है तथा हम अपने पुराने खयाल को ही जोर जोर से पकड़े रह, जिसमें गुप्त धन की विचित्र अवस्था पैदा हो गयी है।

क्या इस सम्बन्ध में हमारी कोई वैसी नीति है, जोकि समुदाय की कीमत पर जमा हो रहे धन को रोकेंगी भूतकाल में अनुचित तरीके से जमा किये गये धन को भी मामने लायेगी? हमें दोनों ही काम करने हैं। भविष्य में धन इकट्ठा न हो सके, इसके लिए शहरी आय पर सीमा का बाधना उतना ही जरूरी है, जितना कि पहले जमा किये गये धन के घातक परिणामों से बचने के लिए उपयुक्त रूप में परिकल्पित विमुद्रीकरण अथवा उतना ही प्रभावी कोई अन्य उपाय करना। गुप्त धन को बिना देर किये किसी भी तरह से प्रकट लाना ही चाहिये। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक प्रणालियों का उपयोग शोषण के लिए किया जायेगा, जिसे लोकतंत्र पर से जनता का विश्वास उठ जायेगा, जिसकी स्थापना के लिए उसने हमें अधिकार सौंपा है, और सामाजिक मूल्य समाप्त हो जायेंगे।

३ मुद्रा-परिचालन

परिचालित मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है। जबकि स्वर्ण नियंत्रण आदेश ने स्वर्ण तस्करी व्यापार में पैसा लगाने का रास्ता बन्द कर दिया है, सटोरिये और मुनाफा-

खोर अब पण्य वस्तुओं में पैसे लगा रहे हैं। जेमा कि आज हम देखते हैं, सिर्फ व्यापारी ही सट्टेबाजी और मुनाफा-खोरी नहीं करते। इसमें सभी वर्ग के लोग लगे हैं, बड़े-बड़े कृषक भी। प्रशोवन विभाग को, जोकि अनाज का व्यापार भी करता है, दिये जानेवाले अग्रिम पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। इस विभाग को प्रशोवन के लिए आवश्यक स्रोत उपलब्ध किये जाने चाहिये, परन्तु व्यापार के लिए नहीं।

४ पी एल ४८०

पी एल ४८० पर बहुत अधिक निर्भर करने की हमारी नीति पर भी वित्तीय दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। पी एल ४८० विविध तरीकों से मुद्रा पूर्ति को और बढ़ाता ही जाता है। मैं पी एल ४८० समाप्त कर देने का आग्रह नहीं कर रहा हूँ। परन्तु पी एल ४८० उत्पादन के मामले में सतोप पैदा करता है। जिस तरह से यह खर्च करने के लिए प्रेरित करता है, वह भी उतना ही खराब है। इसे खतरनाक खपत की वस्तु समझनी चाहिये।

५ निर्यात

हमारी निर्यात नीति पर भी, मूल्यों पर इसके प्रभाव की दृष्टि से पुनर्विचार करने की जरूरत है। किसी भी दर पर प्राथमिक वस्तुओं की पूर्ति के मामले में घरेलू आवश्यकता से निर्यात मांग का समन्वय किया जाना चाहिये।

६ बैंकिंग

आर्थिक अनुशासन की सूची में 'बैंकिंग' का नाम भी जोड़ा जाना चाहिये। भारतीय बैंकिंग किसी भी स्वतंत्र देश की बैंकिंग की तरह नियंत्रण के विरोध में है। यह बहुत ही सूक्ष्मग्राही है। इससे कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। जिन क्षण कोई नियमन और नियंत्रण की बात करता है, पैसे जमा करनेवाला घबड़ा जाता है। तथापि, इसका परिणाम यह निकलता है कि बड़े-बड़े उद्योगपति और

पूजीपति-जिनका बाजार में प्रभाव है— कितनी भी धनराशि प्राप्त कर लेते हैं, जबकि उन व्यक्तियों को बचे-खुचे पर ही निर्भर करना पड़ता है जिनकी कही पहुँच नहीं है। इसमें एक ओर तो आर्थिक स्रोतों का निराशोन्मुख वितरण होने लगा है और दूसरी ओर काफी हद तक धन और आय का सकेन्द्रण हो गया है। इससे प्रतियोगिता नामक चीज क्षेत्र से हटती जाती है, जोकि गैर-सरकारी क्षेत्र को योग्य बनाये रखने तथा उसमें थोड़ी और शालीनता विकसित करने का बहुत बड़ा कारक है। इसका विगुह परिणाम यह निकलता है कि भारतीय बाजार पूजीपतियों के लिए एक सर्वाधिक सुरक्षित बाजार है। कमी है, माग है और प्रतियोगिता नहीं है। इस प्रकार बड़े-बड़े पूजीपति इस हिसाब में काम करते हैं कि उनका कोई मुकाबला करनेवाला ही नहीं है तथा वे नये उद्यमियों को पनपने नहीं दे सकते और मुहमागी कीमत ले सकते हैं। इस काम में उन्हें बैंकों और निवेश न्यासों का पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त है। नये उद्यमियों को निरुत्साहित किया जाता है और प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, जिसमें यदि एकाधिकार नहीं तो अल्पाधिकार का जन्म तो होता ही है।

७. आय, वेतन, मजदूरी और लाभ

यदि मूल्यों को नियंत्रित करना है तो अन्ततः आर्थिक अनुशासन को आय, लाभ, वेतन और मजदूरी की ओर भी देखना है। वस्तुओं की कीमत माग तथा पूर्ति की मात्रा पर ही निर्भर करती है। माग और पूर्ति को प्रभावित करनेवाली हर चीज को नियंत्रित करना है। जब तक हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते, वेतन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। अन्यथा रोक-थाम अनुचित होगी।

तत्काल कार्यवाही के लिए सुझाव

इस प्रकार, मूल्य राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अच्छे अथवा बुरे प्रबन्ध का अन्तिम परिणाम है। अच्छा प्रबन्ध सुनिश्चित करना सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। मेरे मतानुसार तत्काल ही निम्न उपाय किये जाने चाहिये (अ) दीर्घ-कालीन आधार पर, यह

सम्पूर्ण आश्वासन देने की आवश्यकता है कि किसी भी हालत में कृषि उत्पादन में वृद्धि एक निश्चित न्यूनतम से नीचे नहीं गिरने दी जायेगी।* इसका अर्थ होगा कृषि विभाग में अति प्रसगानुकूल नव चेतना। इसी प्रकार असफलता अथवा कमी के लिए जिम्मेदारी सौंपने, कृषि वर्ग के लिए परमावश्यक वस्तुओं को उपयुक्त प्राथमिकता और उसकी पूर्ति एवम उसके साथ ही अच्छी कीमत का ठोस आश्वासन देने की आवश्यकता है। (आ) लघु कालीन आधार पर इन बातों की आवश्यकता है (१) हमारी अर्थ-व्यवस्था में गुप्त धन, एकाधिकार, सट्टेबाजी आदि जैसे विनाशकारी तत्वों को दूर करना। पुराने गड़े धन को उखाड़ने के लिए विमुद्रीकरण कर और भविष्य में गुप्त धन डकटठा न हो, इसके लिए आय पर सीमा बाध कर अथवा सरकार अन्य और किसी भी उपाय से यह काम कर सकती है, (२) जनता के पास जो अतिरिक्त धन है उसे धीरे-धीरे परन्तु निश्चय ही बाहर निकालना, (३) बैंकिंग पर प्रभावी नियंत्रण, (४) गैर-सरकारी क्षेत्र का विकेन्द्रीकरण, (५) घरेलू आवश्यकताओं का निर्यात आवश्यकताओं के साथ समन्वय, और (६) आय, लाभ, वेतन तथा मजदूरी का नियमन।

कहा जा सकता है कि इससे सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी और नियंत्रित समाज का जन्म होगा। इस समस्या को अन्य दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि क्या हम अपनी इन जिम्मेदारियों से बच कर अपनी स्वतंत्रता तथा सम्पूर्ण समाज के अस्तित्व को ही खतरे में नहीं डाल देंगे ?

गांधीवादी सफलताओं का लेखा-जोखा लेना सम्भव है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि जब तक हम कृषि औद्योगिक सभ्यता की ओर धीरे-धीरे न बढ़े, ऐसा नहीं किया जा सकता। अन्तरिम अवस्था में राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में ये उपाय काम में लाये जाने चाहिये। ●

* इस प्रश्न पर मैंने अगस्त १९६४ के खादी ग्रामोद्योग में प्रकाशित 'ग्राम्य विकास' विषयक अपने लेख में विस्तृत विचार किया है।

इजरायल में कृषि-उद्योग समन्वय

वैकुण्ठ ल. मेहता

इजरायल के अनुभव में ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, विशेष कर, उद्योग के साथ खेती के संयोजन, और काम अथवा क्षेत्र के आधार पर कार्य करनेवाले अन्य अभिकरणों की कार्यशीलताओं के साथ समन्वय के मामले में।

ग़ान चन्द वर्षों से कई समाजसेवी और समाज-विचारक हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में व्याप्त गतिहीनता को दूर करने हेतु कृषि-औद्योगिक विकास योजना अपनाने के लिए आग्रह करते आ रहे हैं। उनका कथन है कि इसी गतिहीनता के कारण हमारे सामाजिक विकास के योजित कार्यक्रम के वावजूद देश में गरीबी ने घर कर रखा है। इस विचार की गम्भीरता को समझते हुए ही योजना आयोग ने ग्रामीण उद्योग योजना समिति का गठन किया। सर्वोच्च विचारधारावाले समाजसेवियों में यह दृष्टिकोण उनके द्वारा ग्रामीण कार्यक्रम को दिये गये नये मोड़ और समग्र विकास की योजनाएँ अपनाने के लिए ग्राम इकाई के विकासार्थ किये गये प्रयासों में परिलक्षित है।

मूल उद्देश्य का सर्वोत्तम अनुसंधान करनेवाली सामाजिक संगठन की नयी पद्धति विकसित करने के लिए हमारे प्रयास के दौरान, हमसे से अनेक का ध्यान युगो-स्लाविया और इजरायल जैसे देशों में विकास की वर्तमान पद्धति की ओर आकर्षित हुआ है। ये दोनों ही छोटे देश हैं, और सिर्फ यही साम्यता है दोनों में। युगोस्लाविया के मुकाबले इजरायल नया बसा देश है, दोनों की राजनीतिक प्रणालियाँ अलग हैं, दोनों का सामाजिक स्वरूप भी अलग है। परन्तु दोनों ही अपनी अर्थ-व्यवस्था के संचालन में जनता की अधिकारिक भागीदारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इजरायल में हाल तक कृषि ही राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का मुख्य अंग थी। कृषि में लगे लोग या तो किमी न किमी तरह की कृषि सहकारी

समिति या माल और मेवाओं की पूर्ति करनेवाली अन्य किस्म की सहकारी समितियों के सदस्य हैं। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप आवश्यक रूप से सहकारी है, जैसा कि हमने योजित किया है कि भारत में होना चाहिये।

समग्रता और सहकार

इसलिए अपनी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सहकारी आधार पर बहुविध बनाने में इजरायल को जो अनुभव हुए, वे हम भारतवासियों के लिए बहुत लाभप्रद हैं। हाल ही में प्रकाशित 'एग्रीण्डस'* में इसका सर्वोत्तम विवरण दिया गया है कि इस दिशा में किस प्रकार धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। हमारे देश में कृषि-औद्योगिक विकास कार्यक्रमों के जो प्रवर्तक हैं, उनके पढ़ने योग्य यह पुस्तक है। जब चीन ने जापान पर हमला किया, तब वहाँ (जापान में) गाँवों में सहकारी समितियों का गठन आरम्भ हो गया जिन्हें कि सैनिकों ने पहले ही बाहर से प्राप्त अथवा गहरो में निर्मित, जोकि अब खाली हो गये थे, माल देना बन्द कर दिया था। इस नयी किस्म के संगठन को इडस्को नाम दिया गया। नये विकसित हो रहे अभिकर्ण के लिए लेखक प्रो. हलपेरीन ने एग्रीण्डस नाम जो दिया है, वह एग्रीकल्चर (कृषि) और इण्डस्ट्रीज (उद्योगों) शब्दों के प्रथम शब्दांशों को जोड़ कर दिया है, जोकि दोनों का समन्वय सुझाता है। लेखक के अनुसार संगठन की मूल और मुख्य समस्याएँ हैं (अ) कृषि,

* 'एग्रीण्डस', लेखक प्रो. नईम हलपेरीन (इंटरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रीज), स्टूडेंट एण्ड केगान पाल, लंदन, १९६३, मूल्य ३५ शिलिंग।

सेवाओं और उद्योगों का समन्वय, (आ) प्रदेश के अन्दर पटोसी गाँवों में सहकार।

प्रत्यक्ष है कि इजरायल में कृषि और उद्योग को संयुक्त करने हेतु क्रमबद्ध योजित प्रयास किया गया है और वह भी लेखक के शब्दों में “परम्परागत सम्पत्ति-गाँव” को कम अन्दाज करते हुए नहीं। लेखक बल देते हुए यह कहता है कि गाँव सिर्फ आर्थिक सत्य नहीं है, वह जीवन का एक प्रतिनिधि ढग है। “अतः ग्राम समाज के साथ हमें एक विशेषता जुड़ी रही है।” जब हम भारत में कृषि-औद्योगिक समाज की कल्पना करते हैं तो इन विशेषताओं को बनाये रखने और विकसित करने के अर्थ में ही। औद्योगिक पद्धति ऐसी होनी चाहिये जोकि गाँव के अतिरिक्त श्रमिकों को खपा ले और जीविका के साधनों को, ग्राम समाज के जीवन में बिना किसी प्रकार का व्यवधान अथवा विच्छेद किये बहुविध बनाये। इस पुस्तक में जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि सहकारी ढग से संगठित ग्राम समाज अपने निगमित जीवन की मुख्य बातों और अपनी जीवन-पद्धति को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही उत्सुक है।

कृषि से दूर

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित एक अध्ययन की खोजों के अनुसार आम तौर पर यह पाया जाता है कि विकसित अर्थ-व्यवस्थावाले अधिकांश देशों में लोग खेती से दूर भागते जा रहे हैं। कई देशों में तो कृषि मजदूरों की संख्या में बहुत कमी हो गयी है। भारत में इसकी अवस्था कुछ और ही है। खेती से जीविका प्राप्त करने-वालों का प्रातिगत्य कम नहीं हुआ है, बल्कि कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चूँकि न तो कृषि क्षेत्रों में वृद्धि और न ही सवन खेती का विकास इस वृद्धि की न्यायोचितता सिद्ध करता है, अतः परिणाम यह निकला है कि पूर्ण और अर्ध बेकारों की संख्या बढ़ गयी है। यद्धि लोग गाँवों से शहरों की ओर

जा रहे हैं तो उनमें अधिकांश वेमै ही हैं, जिन्हें गाँवों में काम नहीं मिल पा रहा है, आकस्मिक मजदूरी भी नहीं। युगोस्लाविया और इजरायल की तुलना में भारत में जन-मोत का कम उपयोग इतना अधिक और व्यापक है कि हमें जिस ढग में अपनी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को बहुविध बनाने की कोशिश करनी चाहिये, वह उसमें अलग होना चाहिये जिसका उन देशों तथा जापान जैसे विकसित अर्थ-व्यवस्थावाले देशों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

फिर भी, इजरायल के अनुभवों में बहुत कुछ ऐसा है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर कृषि को उद्योग के साथ जोड़ने में तथा कार्यवाहक अथवा क्षेत्रीय आधार पर काम कर रहे अभिकरणों के कार्यों के साथ समन्वय करने में। उनके विकास की पद्धति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए नीचे एग्रीण्डस की चन्द विशेष-ताएँ पुनः प्रकाशित की जा रही हैं।

- १ कृषि सेवाओं, श्रेणीकरण, प्रशोधन, परिवहन और कृषि उत्पादनों के लिए वित्त प्रदान करने तथा कृषि एवम् अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारखाने और कार्य-गृह स्थापित करने हेतु पड़ोस के अधिकाधिक गाँवों का सहकार प्राप्त करना,
- २ विभिन्न किस्म (किबुज, मोशव आदि) के अधिकाधिक गाँवों को मिल कर क्षेत्रीय सहकार के आधार पर, जिम क्षेत्र के मध्य में एक शहर हो, क्षेत्रीय ग्राम इकाइयाँ स्थापित करना, परन्तु हर किस्म के गाँव को अपनी जीवन-पद्धति को विकसित करते जाना चाहिये,
- ३ जहाँ तक सम्भव हो और तरजीह सहकारी समिति के तौर पर उद्योग का संगठन करना, जिस पर विभिन्न किस्म की प्रवर्तक ग्रामीण सहकारी समितियों तथा उद्योगों के कर्मचारियों का संयुक्त स्वामित्व हो।

एग्रीण्डस के सहकारी गुण को सुरक्षित रखने के लिए आर्थिक पहलू को नियंत्रित किया जाता है, ताकि कृषि, ग्राम समाज और जीवन-प्रद्वति सुरक्षित रहे। अकृषक विभाग के विकास पर चन्द सीमाएँ बाधनी हैं, ताकि कृषि और उद्योग के बीच का सतुलन न बिगड़े। अतः कृषि और सम्बन्धित सेवाओं के क्षेत्र में प्रत्येक गाँव स्वतंत्र रूप में कार्य कर सकता है। ग्राम इकाई द्वारा इस प्रकार अपनाये गये गैर-खेतिहर उत्पादन में कोई बाधा नहीं पहुँचती।

निर्बाध कार्य

इस पुस्तक में सिर्फ सामान्य सिद्धान्तों का ही विवरण नहीं दिया गया है। इसमें वैसे अध्याय भी हैं जोकि इजरायल के विभिन्न क्षेत्रों की अवस्थाओं और आवश्यकताओं का विवरण देते हैं एवम् वर्तमान अभिकरणों, सहकारी समिति, ट्रेड यूनियन और वैधानिक संस्थाओं के कार्य-संचालन को ध्यान में रखते हुए, इन क्षेत्रों की विकास योजनाओं का खाका पेश करते हैं। कुछ अन्य अध्यायों में इस बात का अध्ययन किया गया है कि विकास योजनाओं, कार्यकर्ताओं के संगठनों और सहकारी बस्तियों का नगरपालिका अभिकरणों से किस प्रकार समन्वय किया जा सकता है।

भारत की तुलना में इजरायल का आबादी-घनत्व बहुत कम है। मजदूरों को पूरी रोजगारी मिल रही है, फिर भी लेखक इस बात का आग्रह करता है कि सामाजिक विचारों और प्रणालियों को रोजी पा रहे—जिनमें भूमि पर निर्भर लोग भी शामिल हैं—हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएँ बनानी ही चाहिये। जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पाया है, आम तौर पर यह धारणा है कि विकसित अर्थ-व्यवस्था में भी जबकि कृषि जीविका प्रदान करने में असफल है, तो उद्योग अपने कर्मचारियों को पर्याप्त जीविका नहीं प्रदान करता। अतः स के अध्ययन के अन्त में लिखा है कि हमें क्या दिया जा रहा है, यह एक सामाजिक समस्या है, जोकि समाज-सुधार के लिए अपनाये गये तरीकों से ही हल की जा सकती है। मुख्य आवश्यकता है ग्राम्य जीवन के लिए मजबूत सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करते हुए सतुलित विकास की योजना बनाने की। लेखक का दावा है कि **एग्रीण्डस** के जरिये विकसित सहकार इस तरह के विकास में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को और बहुविध बना, ग्रामों में काम करने की संभावना और बढ़ा तथा ग्राम समाज के विभिन्न वर्गों में और अच्छा सामाजिक सम्बन्ध सुनिश्चित कर काफी योगदान दे सकता है।

पूना ९ अगस्त १९६४

जीवन के आदि से अतः तक मनुष्य न जाने कितने ही सम्बन्ध बनाता और तोड़ता चला जाता है, पर उनमें से कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी याद विस्मृति की सूखी घाटी में अकस्मात् किसी उच्छृंखल पहाड़ी नाले के समान न जाने कंसी हलचल-सी मचा कर उसे आप्लावित कर देती है, और स्मृति के उन लघु पावन क्षणों में प्राणी जिस अलौकिक आल्हाद और अद्भुत सौन्दर्य को पा लेता है, वह अकथनीय है।

— रवीन्द्रनाथ ठाकुर

खादी और ग्रामोद्योगों के लिए संगठनात्मक स्वरूप

अक्षय कुमार करण

संगठन का एक ऐसा नया स्वरूप विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो खादी आन्दोलन को गतिशील तथा प्रभावशाली बना सके। भावी कार्यवाही के लिए लेखक ने प्रस्तुत लेख में कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

पिछले चालीस वर्ष से हम खादी तथा ग्रामोद्योग का कार्य एक दिशा में करते रहे। सन् १९२१ से १९४४ तक खादी एक विशेष दिशा में विकसित हुई। सन् १९४४ में गांधीजी ने उसे एक नया रूप दिया और उन्होंने यह मत दिया कि “जो काते सो पहने और जो पहने वह काते।” उसी समय उन्होंने सारे खादी काम को नयी दिशा देने का सकेत खादी जगत् के सामने रखा। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद खादी नव समाज-रचना का आधारभूत अंग बने, इसकी तरफ गांधीजी ने उसी समय सकेत कर दिया था और कहा था कि हमें गाँव-गाँव में फैल जाना चाहिये।

संगठन के स्वरूप में परिवर्तन

पिछले वर्षों में हमारी दृष्टि खादी काम के विस्तार की तरफ रही। पिछले दस वर्ष में इसका विस्तार भी कम नहीं हुआ। जो काम पहले होता था उससे करीब-करीब बीस गुना काम बढ़ा, लेकिन बीस गुना काम बढ़ने के बाद भी देश की आर्थिक और सामाजिक रचना में हमारा स्थान कहाँ है, उस ओर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जिस ओर जा रहे हैं उस ओर से हमें दूसरी तरफ मुड़ना चाहिये और गांधीजी ने जिधर जाने के लिये सकेत किया था उस तरफ जाने का हमारा प्रयास होना चाहिये। विनोबाजी भी अतः हमारा ध्यान बराबर उस ओर आकर्षित करते रहे हैं। खादी के काम में लगे हुए जितने और लोग थे वे भी समझने लगे कि जिस तरह के संगठन के द्वारा हम काम कर रहे हैं, उसकी सीमा आ गयी है। इस प्रकार के संगठन के आधार पर अब हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर

हमें खादी-काम को व्यापक करना हो और गाँव-गाँव में ले जाना हो तो, आज के संगठन के स्वरूप में हमें परिवर्तन करना ही होगा। आज के संगठन की एक सीमा आ गयी है। इसके द्वारा अब हम उस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते। देश में गरीबी, बेकारी, अर्ध-बेकारी आदि समस्याएँ हैं। आज खादी ग्रामोद्योगों के अलावा दूसरा कोई जरिया दिखाई नहीं पड़ता, जिसके द्वारा देश के गरीब में गरीब व्यक्ति के पाम पहुँच कर उसे हम कोई उपयुक्त साधन दे सकें।

त्रिविध कार्यक्रम

गत ६ अप्रैल को हमने खादी-ग्रामोद्योग के कार्य को इस उद्देश्य की निधि के लिए ही नयी दिशा देने का निश्चय किया। रायपुर सम्मेलन में विनोबाजी के नेतृत्व में सारे खादी और रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं ने सर्व सम्मति से त्रिविध कार्यक्रम अपनाया। वह त्रिविध कार्यक्रम है (१) ग्रामदान, (२) शान्ति सेना और (३) ग्रामाभिमुख खादी, जिसमें ग्रामोद्योग आ ही जाते हैं। अगर हमें खादी तथा ग्रामोद्योगों को स्थायित्व देना है तो खेती और गो-पालन के काम को आधारस्वरूप दाखिल करना होगा और वह काम ग्रामदान से ही होगा। खादी एक विचार है, अहिंसक समाज रचना का प्रतीक है। इसलिये अहिंसक समाज रचना का स्वरूप जमाने के लिए शान्ति सेना भी उसका एक अभिन्न अंग बन जाती है। इस प्रकार तीनों कार्य मिल कर एक ही त्रिविध कार्यक्रम की और एक ही उद्देश्य की पूर्ति के अभिन्न अंग बन जाते हैं यानी बेकारी, बेरोजगारी

मिटाने के लिए खादी-ग्रामोद्योग, उन्हें आधार देने के लिए ग्रामदान, और ग्राम-परिवार को मजबूत और अहिंसक मनाज रचना का स्वरूप देने के लिए शान्ति-सेना। इस प्रकार विकेन्द्रित समाजवादी लोकतंत्र का आधार भी यह त्रिविध कार्यक्रम हो जाता है।

कार्यक्रम की सफलता इन चार बातों पर निर्भर है (क) निष्ठावान, विचारवान और त्यागी कार्यकर्ता, (ख) जन-जागृति, (ग) साधन, और (घ) सगठन। आधारभूत सगठन, कार्यकर्ता, साधन और जन-जागृति होते हुए भी अगर हमारे सगठन के बारे में हमारे विचार स्पष्ट न हों तो हम उपर्युक्त तीनों चीजों का समाज-रचना को व्यवस्थित रूप देने में उपयोग नहीं कर पायेंगे, सलिए सारे कार्यक्रम की सफलता सगठन को व्यवस्थित करने में है।

ग्राम इकाई

हमारे सगठन का स्वरूप क्या हो, यह हमारे लिये विचारणीय है। अब तक सगठन के द्वारा हम जिस हद तक पहुँचे हैं उससे हमें आगे बढ़ना है। आज के सगठन का स्वरूप जितना हमें दे सकता था, उतना दे चुका है। विस्तार की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से, जन-नेतृत्व खड़ा करने की दृष्टि से हमें सगठन के बारे में नये ढंग से सोचना चाहिये। राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने इसके सम्बन्ध में अपनी कल्पना और योजना काफी पहले दे दी थी। उन्होंने उस समय कहा था कि सच्चे ग्रामस्वराज्य की स्थापना के लिए हमें लाखों की सख्या में कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा, जो गाँव-गाँव में जा कर जम जायें और गाँव की प्रेरणा, गाँव का नेतृत्व, गाँव की जिम्मेवारी और गाँव का इन्तजाम गाँववाले स्वयम् कर सकें, ऐसा प्रयास हो।

बापू ने कहा था कि हमारे सगठन की आधारभूत इकाई गाँव है, और सगठन का बड़ा से बड़ा क्षेत्र एक जिला है। जिले में बड़े सगठन की कल्पना को उन्होंने बराबर टाला। खादी और ग्रामोद्योग मंडल और कमीशन की रचना से खादी-ग्रामोद्योग के कार्यक्रम का

बड़ा विस्तार सारे देश में हुआ है। हमारे कार्य ने एक लाख गाँवों को स्पर्श किया है। कमीशन की ओर से सघन क्षेत्र विकास योजना चला कर कुछ प्रयोग भी हुए हैं। उस अनुभव के आधार पर खादी-ग्रामोद्योग को केन्द्र मान कर समग्र विकास योजना के लिए हमने ग्राम इकाई योजना भी आरम्भ की है। उसके भी कुछ अनुभव हमारे पास हैं। इन सभी अनुभवों के आधार पर हमें भविष्य के सगठन के स्वरूप के बारे में सोचना होगा, ताकि हम योजनाबद्ध और व्यवस्थित रूप से आगे बुनियाद जमा सकें, और कार्य-विस्तार में सुगमता हो।

देश में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जनाभिक्रम जगाने के लिए लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण को दृष्टि में रख कर एक नये प्रकार का विकेन्द्रित ढांचा खड़ा हुआ है, जो गाँव और जिले के बीच का है। वह है पचास हजार से लेकर एक लाख तक की आबादी के क्षेत्र का एक विकास खंड। एक-एक गाँव की ग्राम सभा या ग्राम पंचायत और इन पंचायतों के समूह की एक पंचायत समिति, यह इस सगठन का स्वरूप है। यह एक ऐसी इकाई है जिसके दायरे में स्थानीय नेतृत्व खड़ा करके योग्य सेवकों के द्वारा उस सीमा में जिम्मेवारी उठाने और क्षेत्र का विकास करने का मौका और सम्भावना शासन को दिखाई पड़ती है। हम भी जब विकेन्द्रित ढंग से विचार करने हैं तो हमारे सामने भी कार्यकर्ताओं का सगठन, कस्तिन और बुनकर की मुनासिब मजदूरी, खादी और ग्रामोद्योग का आज की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में स्थान, खादी तथा ग्रामोद्योग के पाल का स्थानीय और बाहर की खपत का सगठन, लोगों में खादी और ग्रामोद्योगों की प्रेरणा पैदा करना, लोगों की स्वाभाविक बदलती हुई जरूरतों की तरफ ध्यान देना, वैज्ञानिक साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग आदि सब आते हैं।

इसलिये हमें भी ऐसा लगता है कि त्रिविध कार्यक्रम को ठोस रूप देने के लिए और विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योगों को ग्रामाभिमुख करने के लिए विकास खण्ड

के स्तर पर सगठन को हम पहले खड़ा करे तो एक-दूसरे के पूरक बन कर, प्राप्त शक्ति का अच्छा सयोजन करके, नीचे की इकाई-गांव-को मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं।

बुनाई उपदान योजना की सफलता

ग्रामाभिमुख खादी को सफल रूप देने के लिए मुफ्त बुनाई योजना का कार्यक्रम हमने स्वीकार किया है। इस कार्यक्रम की सफलता भी नीचे के स्तर के सगठन को मजबूत करने में ही है। आज हमारा खादी कार्य जिस तरह में फैला है उसमें एकाएक हम गाँव के स्तर के सगठन को मजबूत करने में शायद सफल नहीं होंगे। आज की वर्तमान सस्था जिले के स्तर पर सगठन को अवश्य ले जा सकती है, लेकिन गाँव और जिले के बीच जो विकास खंड का एक ढाँचा खड़ा हुआ है वह स्वाभाविक रूप से ग्राम विकास का कई मानों में केन्द्र बन रहा है। अगर हम विकास खंड के स्तर के सगठन को एक इकाई मान कर आगे बढ़ें तो मुफ्त बुनाई योजना सफल करने की दिशा में ठोस और योग्य सगठन खड़ा कर सकेंगे। साथ ही गाँव-गाँव में काम फैलाने के लिए स्थानीय नेतृत्व भी प्राप्त हो सकेगा।

तीन स्तर

इस प्रकार हमारे सगठन के तीन स्तर होते हैं (क) ग्राम इकाई, (ख) विकास खंड, और (ग) जिला इकाई। वास्तव में हमारा लक्ष्य तो गाँव-गाँव में पहुँचने का है। एक-एक गाँव में ग्राम परिवार की भावना जगे और सारे गाँव को एक सूत्र में बांध कर गाँव की जिम्मेदारी उठाने के लिए गाँव खड़ा हो, इसके लिए तो ग्राम इकाई ही ठीक होगी, लेकिन इस ग्राम इकाई को सगठित करने के लिए हमें मध्यवर्ती कड़ी खड़ी करनी पड़ेगी जो ग्राम इकाई को सगठित करने और उसे स्वराज्य की तरफ ले जाने के लिए प्रवर्ती सस्था के रूप में काम करेगी। इसलिए हमारा पहला कदम होगा प्रवर्ती सस्था के रूप में विकास खंड के स्तर पर सगठन खड़ा करना। सारे देश में तीन हजार से कुछ अधिक विकास खंड होंगे और अगर आदिवासियों को मिला दें तो चार-पाँच हजार तक हो जायेंगे। अगर हम पहले विकास खंड के स्तर पर कार्य को व्यवस्थित कर लें और एक ठोस नेतृत्व खड़ा कर लें तो गाँव के सगठन को खड़ा करना हमारे लिए आसान होगा।

विकास खंड के स्तर का सगठन दो तरह का होगा (क) रचनात्मक कार्य में रुचि रखनेवाले और विविध कार्यक्रम को भली प्रकार समझनेवाले कार्यकर्ताओं की एक समिति होगी जो गाँव में वितरण पैदा करने, नेतृत्व खड़ा करने और जन-मानस को मजबूत करने में मददगार होगी, (ख) खादी-ग्रामीद्योग, खेती, गो-पालन के काम को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने तथा ग्रामीण अर्थ-रचना को बुनियादी ढंग से बदलने के लिए आर्थिक जिम्मेवारी उठानेवाली दूसरी पजीकृत सस्था होगी या विकास खंड के स्तर पर, आज जो सस्थाएँ काम कर रही हैं उन समस्याओं की शाखा होगी जो सारे काम की आर्थिक बुनियाद मजबूत करने में सक्रिय रूप से काम करेगी। इस प्रकार पहला काम यह है कि विकास खंड के स्तर पर सर्वोदय और लोकतंत्रीय समाजवाद के विचार को माननेवालों तथा सन्निध्य कार्यकर्ताओं व सहानुभूति रखनेवालों की एक समिति हम कायम करें जिसे हम ग्राम स्वराज्य समिति या रचनात्मक समिति का नाम दे सकते हैं। देश के हर एक विकास खंड में इस प्रकार की समिति का जन्म से जल्दी गठन हो जाय, इसको प्राथमिकता देनी चाहिये। इस कार्य की जिम्मेवारी सर्व सेवा सच ही उठा सकता है। उसके नेतृत्व में ही यह कार्य अच्छा होगा। चूँकि खादी कार्य सारे देश में फैला हुआ है, इसलिए सर्व सेवा सच के मार्गदर्शन में खादी सस्थाएँ और कमीशन पूरी तरह से मदद दे सकते हैं।

खण्डीय स्तर

द्वितीय, विकास खंड के स्तर पर जो पजीकृत सस्थाएँ हैं, उनके विषय में भी सोचना है। आज सारे देश में बड़ी-बड़ी सस्थाएँ काम कर रही हैं। पहले आवश्यक यह है कि ये खादी सस्थाएँ अपने काम को विकास खंड के स्तर पर ले जाय और विकास खंड के स्तर को इकाई मान कर गाँव-गाँव में काम फैलाने की जिम्मेवारी लें। इन बड़ी सस्थाओं को विकास खंड के स्तर पर एक सलाहकार समिति बनानी चाहिये, जोकि सरथा की तरफ से उस क्षेत्र के काम की जिम्मेवारी उठाने में मददगार हो। इस तरह सारे देश में बड़ी सस्थाओं के द्वारा कम में कम एक हजार के लगभग विकास खंडों में काम सगठित रूप से किया जा सकता है।

इसके अलावा और भी सस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं। उन्हें भी अपना काम विकास खंड के स्तर पर ही

नियोजित करना होगा। मुफ्त बुनाई योजना को सफल करने के लिए भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि हर एक विकास खंड के स्तर पर कम से कम एक-एक बुनाई केन्द्र हो जाय, ताकि उसके द्वारा धीरे-धीरे हम गाँव के स्तर पर उसे ले जा सकें।

दो प्रकार का संगठन

जहाँ तक सम्भव हो विकास खंड के स्तर पर धीरे-धीरे पञ्जीकृत सस्था हो जाय, जिसमें एक-एक गाँव में जो ग्राम इकाइयाँ खड़ी हो उनके भी प्रतिनिधि हो और जो विकास खंड के स्तर पर एक स्वतंत्र सस्था के रूप में गाँवों में मदद दे और उन्हें हर प्रकार का कच्चा माल तथा कामों के लिए सेवाएँ प्रदान करने का काम पूरी तरह से करे। इस प्रकार विकास खंड के स्तर पर दो प्रकार का संगठन होगा। एक ग्राम नेतृत्व पैदा करने के लिए, और दूसरा गाँव को ठोस आर्थिक ढाँचा देने के लिए। इन दोनों संगठनों के द्वारा ग्राम स्वराज्य की गाड़ी को व्यवस्थित रूप से चलाना होगा। यह संगठन खड़ा हो जाने से फिर इसके द्वारा ही ग्राम इकाई में खेती, गो-पालन, खादी और ग्रामोद्योग का कार्य होगा। गाँव-गाँव में कच्चा माल पहुँचाने, पक्के माल के लिए वहाँ कारीगर तैयार करने, पक्के माल के विपणन की व्यवस्था करने तथा कुछ ऐसे उद्योग जो कि हरेक गाँव में संगठित नहीं किये जा सकते हैं उन्हें विकास खंड के स्तर पर स्थापित करने का काम इस सस्था के द्वारा होगा।

ग्राम इकाई के स्तर पर

ग्राम इकाई के स्तर पर किस प्रकार का संगठन हो, यह भी सोचने की बात है। गाँव के स्तर पर सहकारी समिति ही सुलभ दिखाई पड़ती है, लेकिन इस सहकारी समिति का गठन, इसका विधान तथा इस प्रकार के गठन का विकास खंड के स्तर की सस्था के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रहे, इसके बारे में इसके अनुरूप नियमावली तैयार करनी होगी। आज तक का अनुभव यह बताता है कि ग्राम इकाई के स्तर पर सहकारी समिति और विकास खंड के स्तर पर एक व्यवस्थित पञ्जीकृत सस्था ही योग्य और व्यावहारिक होगी। सहकारी समिति और सस्था का सम्बन्ध किस प्रकार

का हो, यह वैधानिक दृष्टि से कैसे जमेगा, यह भी सोचना होगा।

विकास खंड के स्तर पर संगठन जब खड़ा हो जाय तो, उनका समूह ही जिले के स्तर के संगठन का रूप लेगा। जिन जिलों में बड़ी मस्थाएँ काम कर रही हैं वहाँ तो बड़ी इकाई ही जिला इकाई के रूप में काम कर सकती है, लेकिन जिन जिलों में विकास खंड के स्तर पर मस्थाएँ खड़ी हो जायँ वहाँ उन मस्थाओं को मिला कर एक जिला स्तर पर सघ बनाना ठीक होगा। इस सघ का यह भी काम होगा कि जिन विकास खंडों में कुछ काम नहीं है उन में भी काम को संगठित करने और संगठन खड़ा करने में मदद करे। इसके अलावा यह सघ सारे कच्चे माल की व्यवस्था करेगा, विकास खंड के स्तर पर उत्पादित वस्तुओं में जो फाजिल पक्का माल है उसके बाजार की व्यवस्था करेगा और बाहर की जरूरतों को विकास खंड के स्तर तक पहुँचाने का प्रबन्ध करेगा। प्रारम्भ में ऐसा भी हो सकता है कि आस-पाम के दो-तीन जिलों को मिला कर एक सघ हो।

पक्की कड़ी

इस प्रकार अगर हमें सारे देश में आज की समस्याओं को हल करने के लिए खेती, गो-पालन, खादी तथा ग्रामोद्योगों को ठोस रूप देना है तो संगठन की कड़ी पक्की करनी होगी। आज देश में समस्याओं के हल का एकमात्र तरीका यह रचनात्मक कार्य ही है। एक उद्देश्य, एक विचार और पारिवारिक रूप में जम कर काम करनेवाले खादी-ग्रामोद्योग के हजारों कार्यकर्ता ही आज एक परिवार के रूप में बने हुए हैं। लेकिन देश की जरूरत को पूरा करने के लिए उपयुक्त संगठन हमारे पास नहीं है। उपयुक्त संगठन खड़ा करना ही आज हमारा पहला कर्तव्य है और यह संगठन अगर हम खड़ा कर लेते हैं तो, आज देश में जो ज्वलंत समस्याएँ हैं उनके निराकरण करने में, और हम कार्यकर्ताओं से जो अपेक्षा राष्ट्र-पिता रखते थे या आज बिनोबाजी रखते हैं उसे पूरा करने में, हम योग्य साबित होंगे।

बम्बई १५ जुलाई १९६४

कछार का सामाजार्थिक सर्वेक्षण

सुहास चटर्जी

यद्यपि कछार एक कृषि-प्रधान जिला है, वहा के लोगो के आर्थिक जीवन मे मत्स्य-पालन, फल और बेत उद्योगो का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मणिपुरी घर मे हाथ करवा पाया ही जाता है। औद्योगिक सुविधाएँ भी काफी बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के लड़कियों में भी इन सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है।

असम, विभाजन से पूर्व भौगोलिक दृष्टि में, तीन क्षेत्रों—पहाड़ी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र की घाटी और सुरमा घाटी—में विभक्त था। मिलहट और कछार जिले सुरमा घाटी में थे और आनादी घनत्व वहाँ अधिक था। भौगोलिक दृष्टि से यह घाटी बगाल के मैदानों में जुड़ी हुई थी। चूँकि घाटी क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा बगला भाषी है, इसलिए बगाल के साथ इसका सामाजिक सम्बन्ध भी था। मिलहट और कछार—खाम करके कछार—चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। जिला सदर मुकाम सिलचर 'चाय के कस्बे' के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बराक नदी (जोकि अन्त में सुरमा और कुशियांग के रूप में दो धाराओं में विभक्त हो जाती है) के तट पर बसा मिलचर उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सुरमा घाटी में चाय उद्योग का केन्द्र बन गया। कलकत्ता के साथ इसका अच्छा सम्बन्ध था। इस क्षेत्र में 'स्टीमर कम्पनी' का काम अच्छी तरह फूला-फला। बगाल असम रेलवे सिलचर में जाकर समाप्त होती थी। इससे कलकत्ता और सिलचर का रेल के जरिये बड़ा ठोस सम्बन्ध स्थापित था।

श्रम की उपलब्धि

उत्पादन बढ़ाने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों ने पर्याप्त कोशिश की। मलेरिया से पीड़ित जिले के स्वास्थ्य और साफ-सफाई में सुधार करने का भी उन्होंने प्रयास किया। कालाज्वर फैल जाने से बागानी श्रमिक उसके बुरी तरह गिकार हुए, जिन्हे बिहार और उत्तर

प्रदेश के अकाल-ग्रस्त जिलों से लाया गया था। कुछ सथाल भी श्रमिकों के रूप में काम करने थे। असम और दार्जिलींग के बागानी श्रमिकों के मध्य अन्तर यह है कि दार्जिलींग में इन श्रमिकों की सख्या में अच्छी-खासी तादाद स्थानीय पहाड़ी लोगों की होती है, जबकि कछार में अधिकांश श्रमिक बाहर से आते हैं। मिलहट जनमत-मग्न के वक्त इन श्रमिकों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने मुस्लिम लीग की दलील के अनुसार इन लोगों को 'यायावर' जनसख्या की सजा दी थी। आज स्वतंत्र भारत में असम विधान सभा और सदन में उनका प्रतिनिधित्व है।

उद्योग

उन्नीसवीं शताब्दी में प्रायः सभी बागानों के मालिक यूरोपवासी थे, लेकिन वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ बागान भारतीयों के स्वामित्व में भी आ गये थे। कुछ स्थानीय लोगों ने १८६८ में मिल कर एक जाइट स्टाक कम्पनी खोली थी। कुछ मामलों में भारतीय मालिकों का स्वार्थी यूरोपीयों के साथ संघर्ष हुआ और यदा-कदा उन्हें मात खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। कछार और मिलहट कृषिक उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। धान इस क्षेत्र की प्रधान उपज है।

कछार में विभाजन से पूर्व आबादी घनी नहीं थी तथा कृषिक आबादी में स्थानीय मुसलमान और अनुसूचित

हिन्दू जानियाँ थीं। तुलनात्मक दृष्टि से मुसलमान सदैव ही हिन्दुओं से अच्छे कृषक होते हैं। कछार के मुसलमानों की माली हालत भी हिन्दुओं से अच्छी है। इस क्षेत्र के आर्थिक जीवन में मछली पकड़ने के उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है। वराक और उसकी सहायक नदियों में मछली और कछुए खूब मिलते हैं। मछुए साल भर इन्हे पकड़ कर बेचते रहते हैं— जाड़े और वसन्त में विशेष कर। अतिरिक्त मछलियों को मुखा कर स्थानीय तथा कलकत्ता के बाजार में ऊँचे भाव पर बेचा जाता है। विभाजन का डम उद्योग पर बहुत बुरा अमर पड़ा है। आवागमन के विस्थापन, सामान भेजते समय औपचारिकताएँ बरतने, से सिलहट (पाकिस्तान) और कछार (भारत) दोनों के मछुओं को आवश्यक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं।

जनसंख्या वर्ग

कछार का फल उद्योग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कछार तथा आसपास के पहाड़ी इलाकों की नारंगी बहुत लोकप्रिय है। कलकत्ता के बाजार में मालदह आमों की तरह इन नारंगियों की बहुत माँग है। प्रति दिन लाखों की तादाद में नारंगियाँ हवाई जहाज से कलकत्ता पहुँचायी जाती हैं। सिलचर और करीमगज, जैसे स्थानीय बाजारों तथा छोटे-छोटे गाँवों में भी इन नारंगियों को अच्छा बाजार प्राप्त है। इस व्यापार में काफी तादाद में लोग लगे हैं और यह हिन्दुओं के हाथ में है। पाकिस्तान से आये शरणार्थी अनन्नास उद्योग में लगे हैं। इसके लिए लखीपुर बहुत प्रसिद्ध है। कछार के अनन्नास आकार में बहुत बड़े होते हैं, और स्थानीय रूप से उन्हें 'बनारस' कहा जाता है। यह उद्योग कछार के मुसलमानों के हाथ में है।

इस जिले की आबादी किमानों की है। यह जिला सुरमा घाटी के ऊपरी मैदानों में अवस्थित है। भारत में यह एक सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। इसके अलावा यहाँ की भूमि अभी तक अछूती है। मुख्य कृषि उत्पादन चावल है। प्रायः जिले के प्रत्येक ग्रामीण के पास जमीन है। शरणार्थियों को अपवाद-स्वरूप छोड़ दे तो

भूमिहीन किसानों की समस्या यहाँ नहीं है। श्रमिकों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप जमीन खूब उपज देती है। मुसलमान किसान कठोर परिश्रमी हैं और यह कि उनकी अवस्था हिन्दुओं से अच्छी है। हिन्दू और मुसलमानों की जनसंख्या का प्रातिशत्य क्रमशः ५८ और ३८ है। जिले का उप-सम्भाग हैलाखण्डी इस क्षेत्र का अन्न भण्डार है। बागानी श्रमिक हिन्दू हैं। वे अधिकांशतः बिहारी हैं। शरणार्थियों का प्रातिशत्य २२ है। वे विशुद्ध रूपेण किसान नहीं हैं। सिलचर, करीमगज और हैलाखण्डी शहरों में उनका बहुमत है। कुछ शरणार्थी कृषि और मत्स्य-पालन कार्य में लगे हैं।

कछार में अनेक ऐसे श्रमिक हैं, जो बागान मालिकों से पट्टे (लीज) पर ली गयी जमीन पर खेती करते हैं। चूँकि ऐसी भूमि पर पहले खेती नहीं की गयी थी इसलिए वह बहुत उपजाऊ है। कछार के चाय बागान विशेष प्रकार के गाँव हैं। स्थानीय मणिपुरी लोग खेती और कुटीर उद्योग का काम करते हैं। वे बड़े कठोर मेहनती और बलिष्ठ होते हैं। कभी इन स्थानों की साफ-मफाई बहुत बुरी थी, लेकिन आज सरकारी सहायता के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है।

हाथ करघा बुनाई

भापा की दृष्टि से जिले की आबादी को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ये वर्ग हैं बगला भाषी, हिन्दुस्तानी भाषी और मणिपुरी भाषी। प्रायः ७५ प्रति शत जनसंख्या बगलियों की है। बागानी श्रमिकों की भाषा हिन्दुस्तानी है। कछार में मणिपुरियों की संख्या करीब दो लाख है और वे मणिपुरी भाषा बोलते हैं। जिले में कुछ संख्या नागाओं की भी है— वे समूचे जिले में बिखरे हुए हैं। इस जिले में असमियों की संख्या प्रायः नगण्य है। समूची गैर-बगाली आबादी बगला का इस्तेमाल करती है।

मणिपुरी लोग बुनाई कला के माहिर हैं। जिले के लखीपुर क्षेत्र में प्रत्येक घर में हाथ करघा पाया जाता

है। राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का लखीपुर में एक केन्द्र है, जो समूचे असम में सर्वाधिक आकर्षक है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी भी हाथ करघा बुनाई में लगे हैं। उनमें से ३६ तो परम्परागत बुनकर हैं।

कछार के पहाड़ी प्रदेश में बेत उत्पादन की भरमार है और यहाँ का यह बेत उद्योग मुसलमानों के हाथ में है और विभिन्न प्रकार का उपस्कर, टोकरियाँ तथा अन्य फैंसी सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कामगार कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के हैं। बास उद्योग का क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। सिलचर और करीमगज में कुछ मकानों को छोड़ कर प्रायः सभी घर बास के बने हैं। यहाँ तक कि सिलचर स्थित कछार कालेज का भवन भी बास का बना है। “कमला” नामक समुदाय के बहुत-से लोग इस उद्योग में लगे हैं। वराक और उसकी सहायक नदियों में प्रायः पूरे वर्ष भर बाँस के गट्टे पानी में बहते हुए देखे जा सकते हैं।

शिक्षा

कछार जिला शिक्षा की दृष्टि से भी विकसित है। इस जिले के शरणार्थी लड़के और लड़कियाँ शिक्षा-प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक हैं। जिन छात्र-छात्राओं के घरों में शैक्षणिक वातावरण नहीं रहा है उनमें भी शिक्षा प्राप्ति की यह प्रवृत्ति पायी जाती है। दूर-दूर तक के गावों में भी ऐसा देखा गया है कि छात्र-छात्राएँ पाँच-छ मील चल कर स्कूल में पढ़ने जाती हैं। जिले के सदर मुकाम सिलचर में चौदह हायस्कूल अथवा हायर सेकण्डरी स्कूल हैं। असम के किसी दूसरे कस्बे में इतने स्कूल नहीं हैं। सिलचर में एक लॉ कालेज, ए५ बी टी कालेज, एक पॉलीटेक्नीक स्कूल तथा एक सामान्य स्कूल के

अलावा तीन और कालेज हैं। इस जिले में प्राविधिक शिक्षा का प्रायः अभाव है। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार असम में शिक्षा के प्रातिशत्य की दृष्टि से इस जिले का तीसरा स्थान है।

कछार जिले में साक्षरता - १९६१

एक हजार में	एक हजार पुरुषों	एक हजार
शिक्षितों की संख्या	में शिक्षित पुरुष	स्त्रियों में शिक्षित
		स्त्रियाँ
२८६	४०२	१५८

प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और उमका सगठन अच्छा है। शिक्षकों में महिलाओं की संख्या काफी है। पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम बंगला, हिन्दी और मणिपुरी है।

शहरीकरण

ऊपर में देसत पर असम ग्रामीण लगता है। लेकिन द्वितीय महायुद्ध से इसमें परिपूर्ण परिवर्तन हुआ है। कछार के कस्बों में भारतीय पोशाक का स्थान पाश्चात्य पोशाक ने ले लिया है। गाँवों में आबादी की कमी होनी शुरू हो गयी है, यद्यपि समस्या इतनी गम्भीर नहीं है। विभाजन से पूर्व कछार के प्रमुख शहर सिलचर और करीमगज बहुत छोटे थे, लेकिन आज उनका आकार काफी बड़ गया है। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार सिलचर असम का चौथा सबसे बड़ा शहर है। शहरों में आबादी की वृद्धि से अनेक कठिनाइयाँ खड़ी हो गयी हैं, आवास और साफ-सफाई की समस्या इनमें सबसे महत्वपूर्ण है।

सिलचर (असम) १९ जून १९६४

आर्थिक प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था

मुहम्मद मोहसीन

प्रस्तुत लेख में राष्ट्र के औद्योगिक विकास में उद्योग वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, राष्ट्रीय उद्योग वित्त निगम आदि जैसी माध्यमिक वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का बचत के साधनार्थ-करण की दृष्टिभूमि में विश्लेषण किया गया है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अन्य चीजों के अलावा छोटे और नये औद्योगिक कार्यों के विकासार्थ पूँजी-प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन औद्योगीकरण के दौर में बचत संस्थानों का भी जन्म होता है। जैसे-जैसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जीवन बीमा कम्पनियों, वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, निवृत्ति वेतन और भविष्य निधि तथा डाकघर जैसी बचत संस्थाएँ व्यक्तिगत बचत का अभियान चला कर काफी महत्व प्राप्त कर लेती हैं। अपनी खास जिम्मेदारियों और कानूनी गठन के कारण ये बचत संस्थाएँ घटती-बढ़ती आमदनी करने-वाली नयी संस्थाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित न कर पुरानी तथा जमी हुई संस्थाओं के निश्चित आमदनीवाले ऋण पत्रों में पैसे लगाने को प्राथमिकता देती हैं।

इस प्रकार छोटे व नये उद्योग व्यक्तिगत बचत से वचित हो जाते हैं। फलतः यदि बचत संस्थाओं से औद्योगिक संस्थाओं की ओर निधि प्रवाहित करने का प्रयास नहीं किया जाता है, तो औद्योगिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार पूँजी बाजार की इस कमी को दूर करने के लिए माध्यमिक (विशिष्ट) वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाती है। भारत में बहुत कुछ इन्हीं परिस्थितियों में सन १९४८ से बहुत-सी विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का जन्म हुआ है। इस लेख का उद्देश्य 'भारत

के औद्योगिक विकास में माध्यमिक वित्तीय संस्थाओं की भूमिका' पर प्रकाश डालना है।

औद्योगिक वित्त की मुख्य समस्याएँ

अनुमान है कि भारत ने आर्थिक विकास की 'उठान' (टेक ऑफ) अवस्था में १९५२ में प्रवेश किया।^१ अभी की अवस्था में औद्योगीकरण, बाद की उम्र अवस्था से जबकि औद्योगीकरण "प्रभावशाली घटना" बन जाता है, "जड़ पकड़ता है।"^२ 'उठान' के दौरान नये उद्योग तेजी से बढ़ते हैं और उनमें काफी मुनाफा होता है जिसका अधिकांश भाग फिर से नये उद्योग में लगा दिया जाता है। परन्तु तीव्र आर्थिक विकास के मामले में कम्पनियों के 'आन्तरिक स्रोत' उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रह पाते। परिणामतः उद्योगों को काफी मात्रा में 'बाहरी वित्त' प्राप्त करना होता है। इस प्रकार भारत में, जहाँ कि औद्योगिक विकास की गति मुनाफे की गति से भी तेजी से बढ़ी है, पंच वर्षीय योजनाओं की प्रेरणा में चुकता पूँजी, ऋण, उधार और व्यापारिक वकायों आदि जैसे बाहरी स्रोतों ने पूँजी निर्माण (कुल निश्चित सम्पत्ति) में ८० प्रति शत तक वित्तीय सहायता दी है।^३

१ डब्ल्यू टब्ल्यू रोस्टो दि स्टेज ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १९६०, पृष्ठ २८।

२ वही, पृष्ठ ४०।

३ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, सितम्बर १९६१, पृष्ठ १२२४।

जबकि 'उठान' की प्रारम्भिक अवस्था में पुरानी और जमी हुई सस्थाओं को आवुनिकीकरण, विस्तार और बदलाव के लिए बाहरी स्रोतों की जरूरत पड़ती है, छोटे और नये उद्योगों को दीर्घ-कालीन वित्त प्राप्त करने हेतु बाहरी वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। यह मामला खास कर उन उद्योगों का है जिनका संगठन वर्तमान कम्पनियों का विलय अथवा पुनर्संगठन कर नहीं किया जाता।

नयी कम्पनियाँ

बाहर से पूँजी प्राप्त करने में बड़ी और जमी हुई कम्पनियाँ अपेक्षितया अच्छी अवस्था में हैं। पुरानी सस्था का बाजार में अपना मान-स्थान होता है और उनके पास जमानत देने हेतु पर्याप्त सम्पत्ति भी होती है। छोटी फर्मों के पास ये सुविधाएँ नहीं होती। आय, अपर्याप्त सम्पत्ति और बाजार में उद्योग के संचालकों की पूरी जानकारी न होने से उन्हें (छोटी कम्पनियों) अधिकांश पूँजी चुकता पूँजी के रूप में प्राप्त करनी होती है अर्थात् उद्योग के मालिकों का वह अतिरिक्त योगदान होता है तथा उन्हें बाजार से बहुत ही ऊँची दर पर वित्त प्राप्त करना होता है। इससे उनके विकास में बाधा पहुँचती है। परन्तु नये उद्योगों अथवा सस्थाओं का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रणाली में प्रति-योगात्मक भाव पैदा करते हैं और साथ ही आर्थिक विकास की कुल दर में भी सहायता देते हैं।

वचत के स्वरूप में परिवर्तन होने से नयी औद्योगिक सस्थाओं को वित्त देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 'उठान' की पूर्ण शर्तों में एक यह है कि सरकार और वचत सस्थाओं की वचत उत्पादकता संयोजित करने की प्रारम्भिक क्षमता क्या है। इस प्रकार भारत में १९५०-५१ से १९५८-५९ के बीच सरकारी प्रचार तथा सस्थाओं के सम्पर्क कार्य तथा अन्य कारणों से, जोकि विकास के प्रसंग में आते हैं (जैसे औद्योगीकरण, शहरीकरण, आय का पुनर्वितरण, संयुक्त परिवार प्रणाली के समाप्त होने से स्वाभाविक सामाजिक सुरक्षा में कमी),

व्यावसायिक बैंकों की जमा बीमा वचन, निवृत्ति वेतन और भविष्य निधि, डाक-वचन जैसी सास्थानिक वचतें क्रमशः १८५४ प्रति शत, ३४४ प्रति शत, २७० प्रति शत और २२० प्रति शत बढ़ गयी हैं। इसके विपरीत मुद्रा चलन, स्वर्ण और भौतिक सम्पत्ति जैसी वचतों में क्रमशः ३९ प्रति शत, १६ प्रति शत और १७ प्रति शत की ही वृद्धि हुई है।^४

आर्थिक विकास की पद्धति पर सास्थानिक वचत के विकास का बड़ा प्रभाव है। सामान्यतया सस्थाओं की खास जिम्मेदारियों और कानूनी गठन के अनुसार ही उनमें निवेश किया जाता है। प्रथम सम्पत्ति के एक मिश्रित भाग को उम रूप में रखने का आग्रह करती हैं जिसे तुरन्त ही बिना किसी खास नुकसान के नकद में बदला जा सके, जबकि बाटवाला चन्द क्षेत्रों में निवेश के लिए मना करता है। इस प्रकार पूँजी की सुरक्षा चाहने-वाली सास्थानिक वचतों और जोखिम उठा कर काम करने-वालों के बीच दीवाल खड़ी हो जाती है। इससे अर्थ-व्यवस्था के निजी विभाग के मुकाबले सार्वजनिक विभाग को कुछ लाभ हो जाता है।

निवेश के प्रकार

फिर, नियमित सस्थाएँ अपने दायित्व के अनुरूप ही अपनी निधियाँ लगाती हैं। व्यापारिक बैंक, जिनका दायित्व लघु-कालीन होता है, 'समकक्ष नीति' का अनुसरण करने में दीर्घ-कालीन ऋण देने से कतराते हैं। सहकारी बैंकों द्वारा संयोजित वचतों से अधिकतर कृषि विभाग में पूँजी निर्माण के लिए निधि दी गयी है। डाक-घरों, निवृत्ति वेतन और भविष्य निधियों द्वारा इकट्ठी की गयी वचत रकमों का उपयोग सरकार करती है। जीवन बीमा निगम, जोकि दीर्घ-कालीन निवेशक है, मुख्यतः सरकारी जमानतवाले कार्यों में ही पैसे लगाता है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि सस्थाओं की निवेश नीति

^४ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, अगस्त १९६१, पृष्ठ १२०१।

जबकि 'उठान' की प्राग्भिक अवस्था में पुरानी ओर जमी हुई सस्थाओं को आधुनिकीकरण, विस्तार और बदलाव के लिए बाहरी स्रोतों की जरूरत पड़ती है, छोटे ओर नये उद्योगों को दीर्घ-कालीन वित्त प्राप्त करने हेतु बाहरी वित्तीय स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। यह मामला खाम कर उन उद्योगों का है जिनका संगठन वर्तमान कम्पनियों का विलय अथवा पुनर्संगठन कर नहीं किया जाता।

नयी कम्पनियाँ

बाहर से पूँजी प्राप्त करने में बड़ी और जमी हुई कम्पनियाँ अपेक्षितया अच्छी अवस्था में हैं। पुरानी सस्था का बाजार में अपना मान-स्थान होता है और उनके पास जमानत देने हेतु पर्याप्त सम्पत्ति भी होती

व्यावसायिक बैंकों की जमा बीमा बचन, निवृत्ति वेतन और भविष्य निधि, ठाक-बचत जैसी सास्थानिक बचते क्रमश १८५४ प्रति शत, ३४४ प्रति शत, २७० प्रति शत और २२० प्रति शत बढ़ गयी हैं। इसके विपरीत मुद्रा चलन, स्वर्ण और भौतिक सम्पत्ति जैसी बचतों में क्रमश ३९ प्रति शत, १६ प्रति शत और १७ प्रति शत की ही वृद्धि हुई है।^६

आर्थिक विकास की पद्धति पर सास्थानिक बचत के विकास का बड़ा प्रभाव है। सामान्यतया सस्थाओं की खास जिम्मेदारियों और कानूनी गठन के अनुसार ही उनमें निवेश किया जाता है। प्रथम सम्पत्ति के एक मिश्रित भाग को उस रूप में रखने का आग्रह करती हैं जिसे तुरन्त ही बिना किसी खाम नुकसान के नकद में

आज ही यह फार्म भर कर भेजिये

सकुलेशन मैनेजर,
आगृति, 'ग्रामोदय',
इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
बम्बई-५६ (ए एस)

महोदय,

कृपया मुझे..... .. १९६६ से हिन्दी/अंग्रेजी आगृति का वार्षिक/अर्ध-वार्षिक ग्राहक बनाने की कृपा करें। शुल्क* की रकम भेजी जा रही है। प्रतियाँ निम्न पते पर भेजे

नाम _____
पता _____
डाकघर _____
जिला _____ राज्य _____

भवदीय

दिनांक

हस्ताक्षर

*शुल्क दर: वार्षिक: ₹ रुपये; अर्ध-वार्षिक: ₹ रुपये, एक प्रति: १२ पैसे। कृपया शुल्क की रकम अस्मिन्ष्ट पकाउण्ड्स ऑफिसर (केश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ (ए एस) के पते पर भेजे।

कृपया ध्यान दें कि यह फार्म केवल सूचना के लिए है।

ने ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियों की आवश्यकताओं और स्रोतों के बीच शून्य का निर्माण कर दिया है। इस अन्तर की विगलता का अन्दाज इस तथ्य से मिल सकता है कि १९५१-१९५८ की अवधि में पूँजी इजरा नियंत्रक द्वारा ५ अरब ५५ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी, जिस पर कम्पनियाँ कुल ३ अरब १ करोड़ रुपये प्राप्त कर सकी अर्थात् उम अवधि में स्वीकृत रकम का करीब ५४ प्रति शत ही।^५ आवश्यक पूँजी एकत्र करने में कठिनाई सम्पूर्णतः देश में वचन की कमी के कारण ही नहीं है, बल्कि जीवन बीमा कम्पनी तथा वचन सस्थाओं द्वारा औद्योगिक विकास कार्यों में वित्तीय सहयोग देने में बेरुखी से भी है।

फिर, नयी सस्थाओं के घटते-बढ़ने अर्जक ऋण-पत्रों में पूँजी न लगा कर जमी-जमायी व्यापारिक सस्थाओं के निश्चित अर्जक ऋण-पत्रों में पूँजी लगाने को प्राथमिकता देना भी कम्पनियों के वित्तीय ढाँचे में मौजद उच्च ऋण अनुपात के लिए जिम्मेदार है। उदाहरणार्थ, १९५६-६० की अवधि में कम्पनियों के कुल स्रोतों के अनुपात में ऋण का प्रति शत ३०.१ था, बाहरी स्रोतों का ५१.५ प्रति शत, निश्चित परि-सम्पत्ति का ४३.९ प्रति शत। कुल स्रोतों में साधारण हिसों का प्रति शत मरि ९.८ अथवा बाहरी स्रोतों का १६.७ प्रति शत है। कम्पनियों के वित्तीय स्वरूप में ऋण-पत्रों और अधिमान अशों का अपेक्षतया कम महत्व है। उनका योगदान कम्पनियों के कुल स्रोतों के एक प्रति शत से अधिक नहीं है।^६

वचन के सास्थानीकरण का प्रभाव

कम्पनियों में भारी कर्ज का मौजद रहना विकासशील

^५ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, फरवरी १९६१, पृष्ठ १७७।

^६ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, सितम्बर १९६१, पृष्ठ १४६४।

निगमित विभाग के लिए कमजोरी का एक चिन्ह है, क्योंकि इसके अन्तर्गत कम्पनियाँ विस्तार और प्रवर्तन की जोखिम नहीं उठा सकती। परन्तु इस वित्तीय स्वरूप को अपनाने में कम्पनियों को बाजार की परिस्थितियों के निर्देश के अन्तर्गत काम करना पडा है, क्योंकि वे बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है वचन सस्थाएँ, जोकि व्यक्तिगत वचन की मात्रा दिनोदिन बढ़ाती ही जा रही हैं, अपने अनिश्चित स्वभाव के कारण इक्वीटी में बहुत कम पूँजी लगाती हैं। भारत में सस्थाओं को डिबेंचर भी मुवाफिक नहीं बैठते, क्योंकि उममें उन्हें सरकारी ऋण-पत्रों में रुपया लगाने जितना ही लाभ मिलता है, जबकि डिबेंचर में जोखिम अधिक है। यह जीवन बीमा निगम के विभागीय स्वरूप से जाहिर है, जोकि निगमित ऋण-पत्र में मरवे अधिक पूँजी लगानेवाला है। निगमित ऋण-पत्रों में जीवन बीमा निगम का निवेश इसकी कुल सम्पत्ति का मरि १४.८ प्रति शत है, जिसमें साधारण अशों का योग परिमम्पत्ति का ७.६ प्रति शत है, अधिमान अश परिमम्पत्ति का ३.३ प्रति शत है और ऋण-पत्र ३.८ प्रति शत। सस्थाओं द्वारा लगायी गयी सीमित पूँजी कम्पनियों की विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत अपर्याप्त है। अतः कम्पनियों को पूँजी बाजार के असंगठित विभाग से मजबूरन ऋण लेना पडता है। इससे छोटे उद्यमियों को नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास सस्थाओं की निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय जमानत देने के लिए कुछ खाम नहीं होता।

अतः यह स्पष्ट है कि वचन का सास्थानीकरण, जोकि देश के औद्योगीकरण का परिणाम है, अपेक्षतया कमीवाले और विकासशील क्षेत्रों में पूँजी के प्रवाह में बाधा पहुँचाता है। यदि उत्पादक आधार पर निधि को प्रवाहित करने का प्रयाम न किया गया तो भविष्य में औद्योगिक विकास में बाधा पहुँचगी।

उनके महत्वपूर्ण होने पर भी हम बचत संस्थाओं पर औद्योगिक वित्त की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप में हल करने के लिए अधिक दबाव नहीं डाल सकते। बचत संस्थाओं की अपनी सीमाएँ हैं; क्योंकि वे अपने भागीदारों की निधि की न्यासी हैं। न्यासी के तौर पर वे औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी और जोखिम नहीं उठा सकतीं। और न ही उन्हें अपने भागीदारों के हित को बन्धक रखने तथा एक निर्धारित व्याज दर पर सरकार को निधि दे देने की सलाह दी जा सकती है। दोनों ही विचार अति छोर पर हैं और देश के आर्थिक विकास पर उनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

माध्यमिक वित्तीय संस्थाएँ

अतः औद्योगिक वित्त की समस्या को माध्यमिक वित्तीय संस्थाओं के जरिये हल करने की कोशिश की जाती है। विशेषज्ञ संस्थाएँ, जोकि औद्योगिक विकास के सहायतार्थ जन्म लेती हैं, प्रत्यक्ष रूप में बचत संयोजन नहीं करतीं बल्कि अपनी निधि बचत संस्थाओं से अंश पूँजी, ऋण-बाण्ड आदि के जरिये प्राप्त करती हैं। संस्थाओं द्वारा जारी किये बाण्ड की गारण्टी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें देती हैं। अतः वे प्राथमिक बचत संस्थाओं की पूँजी के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार माध्यमिक वित्तीय संस्थाएँ प्राथमिक बचत संस्थाओं को उस जोखिम से मुक्त कर देती हैं जोकि विकास-शील अर्थ-व्यवस्था में अन्तर्निहित हैं। इस प्रकार भारत में १९४८ से बड़ी संख्या में माध्यमिक वित्तीय संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे उद्योग वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, राष्ट्रीय उद्योग वित्त निगम, भारतीय उद्योग ऋण और निवेश निगम। ये सब सरकार के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग से ही सामने आये हैं। ये संस्थाएँ अब भारत में औद्योगिक वित्त के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान कम्पनियों द्वारा बाहर से प्राप्त वित्त का एक-तिहाई है जोकि संगठित निजी औद्योगिक

विभाग द्वारा वर्ष में कुल निश्चित निवेश का करीब १५ से २० प्रति शत है।^७

यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण योगदान है, संस्थाओं द्वारा यदि अपेक्षतया नहीं तो निश्चित रूप में दिनोंदिन अपनी भूमिका बढ़ते जाना आवश्यक होगा। परन्तु अभी माध्यमिक वित्तीय संस्थाओं के पास अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने हेतु पर्याप्त स्रोत नहीं हैं। निवेश वित्त निगम का उदाहरण सामने है जिसके पास उसकी सामर्थ्य से कहीं अधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र आये हैं, जोकि यह दर्शाता है कि वर्तमान वित्तीय संस्थाओं के स्रोतों को बढ़ाने की बहुत जरूरत है।

फिर, विशेषज्ञ माध्यमों द्वारा दी जानेवाली सहायता, निवेश ऋण निगम को छोड़ कर, मुख्यतः ऋण के रूप में ही दी जाती है। कम्पनियों के वित्तीय स्वरूप में ऋण का इतना बड़ा अनुपात जो पाया जाता है उसका महत्वपूर्ण कारण उसे ही मानना चाहिये। सन् १९६१ में उद्योग वित्त निगम अधिनियम को संशोधित किया गया, ताकि निगम उद्योग को साम्य (इक्विटी) पूँजी उपलब्ध करने योग्य बन सके। परन्तु जब तक निगम के पास पर्याप्त स्रोत नहीं हो जाते, इस समस्या का हल होने की आशा नहीं है।

जमानत की कठोर कसौटी

उद्योग वित्त निगम और निवेश निगम ने यद्यपि नयी संस्थाओं की स्थापना के लिए अपनी निधि का आधे से ज्यादा का वितरण कर दिया, परन्तु वह निधि बड़ी कम्पनियों को ही दी गयी है; क्योंकि छोटी कम्पनियों को वित्त देने का अधिकार राज्य वित्त निगमों को ही है। ऋण मंजूर करने में भी निगमों ने जमानत की बहुत कठोर कसौटी निर्धारित की है। सामान्यतया, ऋण-

७. रोजेन जार्ज : सम एक्सपेक्ट्स ऑफ इण्डस्ट्रियल फायनेन्स इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, लंदन; १९६२; पृष्ठ : १०४।

विमर्श गोचर परिसम्पत्ति की जमानत पर ही ऋण दिया जाता है। वह पहले ही यह मान लेता है कि पर्याप्त साम्य पूँजी वर्तमान है। ऋण परिसम्पत्ति-मूल्य वे आधे तक ही दिया जाता है। इस प्रकार निगम काफी सुरक्षित कदम उठाता है। उद्योग वित्त निगम से ऋण लेने में निगम के जाने पहचाने उद्यमियों की व्यक्तिगत जमानत भी देनी पड़ती है। फिर, इन शर्तों की पूर्ति करना नयी कम्पनियों के लिए बहुत कठिन है। अतः वे निगम से काफी सहायता प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। इन शर्तों में ढिलाई करने के विषय में निगम की सीमाएँ भी समझी जा सकती हैं। अधिकांश विशेषज्ञ सस्थाएँ सरकार द्वारा प्रवर्तित अभिकरण हैं, अतः वे ससद के प्रति उत्तरदायी हैं। इस कारण उन्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है।

औद्योगिक विकास बैंक

हाल में वर्तमान सस्थाओं की भूमिका को विस्तृत करने अथवा विकल्प अभिकरणों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव किये गये हैं। उनमें सम्भवतः सर्व प्रमुख हैं, उद्योग विकास बैंक की स्थापना करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया निर्णय। यह नया बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के उच्चस्थ समन्वयकारी अभिकरण के रूप में काम करेगा। यह उद्योग वित्त निगम और पुनर्वित्तदात्री निगम को मार्गदर्शन देगा और कुछ समय बाद दोनों निगमों को अपने अन्तर्गत ले लेने का अधिकार भी इसे है। उद्योग विकास बैंक सार्वजनिक और गैर सरकारी दोनों ही विभागों को मदद देगा। परमावश्यक परियोजनाओं को वित्त देने के मामले में यह बहुत ही उदार नीति का अनुसरण करेगा, भले ही वे सामान्य व्यापारिक स्तर के अनुरूप न भी हों।

यह बैंक वर्तमान सभी सस्थाओं को मिला कर एक केन्द्रीय वित्तदात्री सस्था के रूप में काम करेगा ताकि राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (जिसने ऋण देना अब बन्द कर दिया है) छोटे-छोटे उद्योग निगमों और उद्योग वित्त निगम में होनेवाले दोहरे काम को कम किया जा सके। उद्योगों के लिए आनुपगतिक नीतियों के निर्माण की दिशा में यह पहला कदम है।

निष्कर्ष

यह नयी सस्था सीधी भारत सरकार के संरक्षण में काम करेगी। इस वजह से इसे सरकार से व्याज रहित ऋण मिलेगा और यह रिजर्व बैंक के अतिरिक्त कोष का भी इस्तेमाल कर सकेगी। तथापि, आगे चल कर बैंक को स्वावलम्बी सस्था बन जाना चाहिये। स्रोत निर्माण की दिशा में इसे प्राथमिक वचन सस्थाओं को उच्च व्याज दर देकर पर्याप्त प्रेरणा देनी चाहिये। अभी व्यावसायिक बैंक और जीवन बीमा निगम विशेषज्ञ सस्थाओं में अपनी परिसम्पत्ति का नगण्य भाग निवेश रूप में लगाते हैं। उदाहरणार्थ, जीवन बीमा निगम विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के ऋण-पत्रों में जीवन बीमा कोष का सिर्फ एक प्रतिशत ही लगाता है, क्योंकि विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रदत्त व्याज दर अधिक नहीं है। यदि जीवन बीमा निगम को अपनी निधि का करीब छ. अथवा सात प्रतिशत इसमें लगाने का प्रेरित किया जाय और व्यावसायिक बैंक भी तदनुसार अपनी नीति में संशोधन करें, तो उद्योग विकास बैंक को और अधिक निधि मिल जायेगी। इससे भारत के औद्योगिक विकास में यह अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका निभा सकेगा।

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) १८ जुलाई १९६४

ग्रामीण उद्योग और लोकतांत्रिक समाजवाद*

वै. पद्मनाभन

हमारे सामाजिक स्वरूप की अनिवार्यताएँ इस बात की आवश्यकता पर जोर देती हैं कि हम एक कृषि-औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए अपने को लगा दें। ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक स्वरूप का विकास करना होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल कारीगरों के मध्य उद्यमशील प्रतिभा और प्रबन्ध कौशल का विकास करना भी आवश्यक होगा।

यद्यपि भारतीय समाज व्यवस्था से सभी परिचित हैं फिर भी, इसे कृषि-औद्योगिक ग्रामीण आधार के विकास अथवा कृषि को केन्द्रित औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के लिए अन्न और कच्चे माल का उत्पादन करनेवाला बनाने की आवश्यकता की एक अलग दृष्टि से ही समझना अभी भी बाकी है। यह सर्वविदित है कि भारत गाँवों का देश है। इसकी अधिकांश आबादी गाँवों में बसती है और उसके पास अवकाश के अपरिमित क्षण हैं। परन्तु ओर भी कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका जानना आवश्यक है, यदि सम्पूर्ण देश के लिए एक विकास पद्धति बनानी हो।

इन में से जिस तथ्य की व्यापक जानकारी करायी जानी चाहिये वह यह है कि आबादी के सर्वोच्च १ प्रति शत लोगों की संयुक्त आय निचले २५ प्रति शत लोगों की कुल आय से भी बड़ी है। दूसरा तथ्य यह है कि ग्रामीण आबादी का ७० प्रति शत प्रति दिन सिर्फ ५० पैसे ही खर्च कर सकता है, भले ही हमारी राष्ट्रीय आय का आधा कृषि से ही प्राप्त होत हो, और सिर्फ १७ अथवा १८ प्रति शत ही उद्योगों से प्राप्त होता है तथा संगठित विभाग से सिर्फ ९ अथवा १० प्रति शत। हम जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उन में कृषि उत्पादन से बनी चीजों

की मात्रा काफी अधिक है, और दूसरे देशों में उद्योगों की तेजी से विकास कर प्राकृतिक उत्पादनों के विकल्प स्वरूप जो अधिकाधिक कृत्रिम वस्तुएँ प्राप्त की जा रही हैं, उनसे दृढ़ खतम हैं ही।

परिवर्तनशील सामाजिक स्वरूप

विश्व में हो रहे इन महत्वपूर्ण ओर बड़े परिवर्तनों के प्रभाव से हमारे देश के सामाजिक ढाँचे में भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। शीघ्र ही शिक्षा का प्रसार स्कूल जानेवाले तमाम बालकों तक हो जायेगा, जोकि आगे चल कर जागृत नागरिक बनेंगे और जिनमें धन्यो, कोई जरूरी नहीं कि कृषि ही हो, के जरिये अपने परिवार की आमदनी में हिस्सा बँटाने की लगन होगी। देश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि अथवा उद्योग से भी अधिक महत्वपूर्ण विभाग व्यापार बनता चला जा रहा है, जिसमें लाभ की अधिक सम्भावना है और इसका परिणाम यह है कि समाज के विकास के लिए जिन उद्यमी प्रतिभाओं की अत्यावश्यकता है, वे सब व्यापार की ओर खींची चली आ रही हैं।

मद्रास राज्य में बड़े पैमाने पर गाँवों में बिजला का तीव्र विस्तार वह दूसरी बात है, जिस पर विचार करना आवश्यक है।

अब यदि हम विकास कार्यक्रम बनाने की तैयारी करें तो यह महसूस करेंगे कि देश की अर्थ-व्यवस्था में शीघ्र विकास और परिवर्तन लाने के लिए कृषि-

* मद्रास में दिनांक १६ से १८ जुलाई १९६४ तक सम्पन्न लोकतांत्रिक समाजवाद विषयक गोष्ठी के लिए तैयार किये गये शोध लेख पर आधारित।

औद्योगिक समाज की दृष्टि से सोचना आवश्यक है। अकेली कृषि इस बड़ी जागृत और शिक्षित आबादी को, जिसे परिस्थितियों से मजबूर होकर गाँवों में ही रहना पड़ सकता है, रोजगारी नहीं दे सकती। औद्योगिक विभाग की प्रेरणा से ही कृषि के परम्परागत कला-कौशल में परिवर्तन होगा। अतः कृषि विकास और गाँवों के जीवन-स्तर में सुधार के हित में, नये वर्ग के युवकों को रोजगारी देने के अलावा—अन्यथा कहीं वे निरुत्साहित और विरक्त वर्ग में शामिल न हो जायें—कृषि और उद्योग को भी साथ ही साथ विकसित होना है।

ग्रामीण कारीगरों की भूमिका

इस प्रकार गाँवों में उद्योगों के विकास की आवश्यकता स्वीकार करने के बाद हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस प्रकार का संगठन तैयार किया जाना चाहिये। उद्योग के विकास के लिए उद्यमी और प्रबन्धकीय प्रतिभाएँ परमावश्यक हैं। इन प्रतिभाओं को एक नये वर्ग के लोगो ने, जिनका काफी प्रभाव है, हथिया लिया है, जिसका परिणाम यह निकला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास ने एक दक्ष कारीगर को मजदूर और उद्यमियों को छोटा पूँजीपति बना दिया है। यदि समाजवाद की प्राप्ति करनी है तो 'औद्योगिक समाज के लिए आयोजन' अन्तिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नीचे से करना होगा। इस प्रक्रिया में दक्ष कारीगरों को मुख्य भागीदार होना होगा। फिर, समाजवाद को वास्तविकता का रूप देने के लिए इन कारीगरों को सहकारी सघों में संगठित होना होगा।

हमने हमेशा छोटे उद्योगों के सहकारी ढंग से काम करने पर जोर दिया है, जैसे निर्माण और व्यापारिक इकाइयों की सहकारी समितियाँ, कच्चे माल खरीदने-वाली तथा उत्पादन का माधन रखनेवाली एव सदस्यों को बहुत कुछ मजदूर समझनेवाली समितियाँ। इस प्रकार की समितियों की अपनी ताकत है, अपने लाभ हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कारीगरों को शामिल करने के लिए इस प्रकार की पद्धति से मुख मोड़ना होगा। यदि

इस बात की जाँच करे कि हम देश में किस प्रकार के कृषि-औद्योगिक आधार का निर्माण करना चाहते हैं, तो एक भिन्न किस्म की समिति की आवश्यकता स्पष्ट हो जायगी।

उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण

गाँवों में हजारों की सख्या में बढ़ई, लोहार, चर्म-शोधक, कुम्हार, ताड़-छेदक आदि जैसे परम्परागत कारीगर हैं। शैक्षणिक सुविधाओं के प्रमाण से परिवर्तित पद्धति होने पर भी ये कारीगर वर्ग, जिन्होंने निशुल्क शिक्षा का लाभ नहीं उठाया है, काफी सख्या में मौजूद रहेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन करते रहेंगे। उन्हें अपनी कारीगरी को काफी मात्रा में विकसित करना है। परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षण केन्द्रों में लाना हमेशा एक समस्या बनी रही है। सम्भवतः एक सहज उपाय यह होगा कि गाँवों के कारीगरों को छोटे-छोटे दलों में विभक्त कर उनके रहने की जगह के आसपास ही नयी तकनीकों और मुबरी कारीगरी की जानकारी दी जाय। कुछ और स्पष्ट रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वडइयों और लोहारों के मामले में अभी भी जो लोग अपने धर्मों में लगे हैं उन्हें छोटे-छोटे ओमारे प्रदान किये जायें, जोकि ५ से १० कारीगरों की जमात के लिए पर्याप्त हो। उनकी कारीगरी में सुधार करने के लिए रियायती दर पर औजार बाँटे जायें।

सामूहिक ओसारे

आधुनिक तकनालाजी अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए सभी कारीगरों को सामूहिक ओसारे में काम करने के लिए चन्द शक्ति चालित यंत्र दिये जायें, जैसे गोल आरी, वर्मा, जोड़नेवाला यंत्र, धौकनी आदि। इन ओमारों की देखभाल पचायत संगठनों के जरिये विस्तार अधिकारी (उद्योग) करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रकार के छ सामूहिक ओसारे रखनेवाली पचायत के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जा सकती

हैं, जोकि धूम-धूम कर कारीगरों को औजारों और यंत्रों का उपयोग करना सिखायेगा। योजना को सफल और प्रभावी बनाने के लिए दूसरा कदम होगा सम्पूर्ण पचायत मण्डल के लिए, एक कारीगर सेवा समिति का गठन करना, जिसमें सामूहिक ओसारे, औजार और यंत्र प्राप्त सभी कारीगर आ जायेंगे। यह समिति कारीगरों को आर्थिक सहायता देगी, कच्चे माल उपलब्ध करायेगी और तैयार माल की बिक्री में मदद देगी। इससे कारीगर अभी कृपकों की जो सेवा कर रहे हैं वह करते रह सकेंगे तथा उनके लिए उत्पादन के नये द्वार भी खुल जायेंगे। यह समिति दरवाजे और खिड़कियाँ, शहतीर, कृपि औजार और स्कूल तथा कार्यालयों के लिए उपस्कर (फर्नीचर) बनाने के काम भी हाथ में ले सकती है। इस प्रकार के सगठनात्मक विकास की विशेषता होगी—ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के लिए सहकारी प्रयास में कारीगरों द्वारा सक्रिय भागीदारी।

इसी प्रकार की सुविधाएँ कुम्हारों को भी दी जा सकती हैं, जिन्हें ओसारे के अलावा मिट्टी गूथने के लिए छोटी-छोटी मशीनें, मिट्टी धोने की टकिया, सामूहिक भट्टियाँ बिक्री के लिए परिवहन सेवाएँ आदि दी जा सकती हैं। कुम्हारों की दक्षता उन्हें मुराही, जल-गीतक, खपरैल, नलिकाएँ, लाख की पालिशवाले बर्तन आदि जैसी चीजों के निर्माण की नयी तकनीकें बना कर विकसित की जा सकती हैं।

चर्मकारों के लिए

यह कार्यक्रम बड़ी सख्या में पाये जानेवाले ग्रामीण चर्म-शोधकों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। बिजली के प्रसार के कारण मशक की माग बहुत घट गयी है और जब तक वे जूते और चर्म वस्तुओं के लिए बहुत ही मुन्दर ढग से शोधित चमड़ा उत्पादन की ओर नहीं मुड़ते, उनके मित जाने की आशंका है। चर्म-शोधक बहुत ही पिछड़े हुए कारीगर हैं तथा उन्हें सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें चर्म-शोधन ओसारे,

वाटल छाल और चर्म-शोधन के अन्य वैज्ञानिक तरीके उपलब्ध कराने पर, उनके द्वारा की गयी चर्म-कमाई का स्तर बहुत सुधर जायेगा। इस तरह के चर्म-शोधन ओसारे के एक समूह के लिए एक समापन केन्द्र हो सकता है, जिसमें कि चन्द चर्म-शोधन ढोल और यंत्र होंगे तथा उन पर उस सेवा समिति का अधिकार होगा जिसके सदस्य क्षेत्र के सभी चर्म-शोधक होंगे। अन्य किस्म के कारीगर भी हैं। उपर्युक्त आधार पर उनके लिए भी योजनाएँ बनानी होंगी। ये चन्द तरीके हैं जिनके जरिये कारीगरों की लुप्त हो रही कारीगरी को सुधारा जा सकता है। नये उद्योगों को भी विकसित करना होगा। उन्हें अधिकांशतः प्रगोधन कार्यों तक ही सीमित रखना होगा।

तकनालाजी का स्तर

सर्वाधिक प्रमुख कारक है तकनालाजी का एक स्तर अपनाता जोकि लुप्त हो रही कारीगरी के लिए एक बहुत ही ऊँची चढान साबित नहीं होगी और देश के साधनों के अन्तर्गत ही होगी और मैकडो-हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगारी देने की क्षमता रखेगा। श्री ई एफ शुमाशेर के शब्दों में “भारत में श्रमिकों का ‘आधिक्य’ है और पूँजी की ‘कमी’ तथा उसे तकनालाजी के एक स्तर की जरूरत है। अथवा प्रति कार्य स्थान पीछे पूँजी निवेश की जोकि पश्चिमी देशों की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है, जहाँ कि पूँजी का ‘आधिक्य’ है और श्रमिकों की ‘कमी’। अतः प्रारम्भ के लिए मेरा यह मुद्दाव है कि निर्माण उद्योगों में प्रति कार्य स्थान पीछे औसत निवेश—ग्रामीण औद्योगीकरण के व्यापक प्रसार के लिए उपयुक्त—एक हजार रुपये होगा, जिसमें भवन-निर्माण का खर्च शामिल नहीं है।”

संगठित विभाग के पीछे-पीछे

यदि हम देशी तकनीक का ऐसा स्तर प्राप्त करने में सफल होते हैं तो औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ी सख्या में ग्रामीण केन्द्रों का निर्माण करना संभव होगा।

तब सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू आयोजन स्तर पर ठोस नीति बनाने से संबंधित होगा, ताकि उन्हें विकास का मौका मिले और उस विभाग से अकेले ही मुकाबला न करना पड़े जोकि उन्नत तकनीको का इस्तेमाल करता है। कमौटी यह होनी चाहिये कि अधिकांश स्थानीय आवश्यकताएँ ग्राम स्तर पर ही पूरी हो जायँ। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता के शब्दों में “सरकारी क्षेत्र में चन्द परम्परागत उद्योगों को विकेन्द्रित करना होगा और उन्हें विकसित हो रही कृषि-औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में शामिल करना होगा।” विकास का अगला आवार होगा— लघु उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण विभाग को औजारों, यंत्रों, गँवों में न तैयार हो सकने लायक पुर्जों तथा यंत्र-मशीन फिट करने के मामले में सक्रिय सहयोग देना। इसी प्रकार पूर्ण संगठित बड़े उद्योगों

को भी, जोकि विशेष कर कच्चे माल के प्रशोधन और उन वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित हैं जोकि समाज की अत्यावश्यकताओं की पूर्ति करती हैं; अपने वैसे उत्पादन को सीमित अथवा बन्द कर देना चाहिये ताकि वे ग्रामीण और लघु उद्योग विभाग पर उल्टा प्रभाव न डाले।

मैंने अपनी बातें ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों तक ही सीमित रखी हैं तथा औद्योगिक विभाग के बड़े विकास के साथ समन्वय के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। वर्तमान सन्दर्भ में, यदि शीघ्र परिणाम प्राप्त करना और राष्ट्रीय आय को काफी बढ़ाना है तो, अब तक बहुत अधिक नजरअंदाज किये गये ग्रामीण उद्योगों पर ज्यादा जोर देना ही होगा।

युग का महान व्यक्ति वही है, जो अपने युग की आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करे, युग को बताये कि उसकी आकांक्षाएँ क्या हैं और उन्हें पूरी करे। वह जो कुछ करता है, वह उसके युग का स्पन्दन और सार तत्व होता है, वह अपने युग को परिपक्व और परिमार्जित करता है।

— हवाट इज हिस्ट्री में इ एच कार द्वारा हीगल का उद्धरण, पेग्विन बुक्स, लंदन; १९६४।

विभिन्न ग्रामोद्योगों का सापेक्षिक महत्व

देवेन्द्र कुमार गुप्त

लेखक का सुझाव है कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न ग्रामोद्योगों के लिए बटित की जानेवाली निधि उनके महत्व के अनुपात में होनी चाहिये। उसका निर्णय इन बातों पर विचार कर किया जा सकता है। प्रथम, एक आम आदमी के पारिवारिक बजट में इन उद्योगों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सामग्री का सापेक्षिक स्थान, द्वितीय, उनका निवेश-उत्पादन-अनुपात, तृतीय, उनके द्वारा प्रदत्त रोजगारी तथा उनका उत्पादन, और चतुर्थ, प्रत्येक उद्योग के भावी विकास की क्षमता।

सभी ग्रामोद्योगों का समान महत्व नहीं होता और उन सबके विकास की सम्भाव्यताएँ भी समान नहीं होती, इसलिए देश की अर्थ-व्यवस्था में उनके सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अतएव कार्यक्रम और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के मन्दर्भ में प्रत्येक उद्योग के सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन करने के लिए कोई माधन मालूम करना चाहिये। इस दृष्टि से देखने पर निम्न बातों पर विचार करना वाछनीय होगा।

विभिन्न ग्रामोद्योग

यदि हम खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले पन्द्रह उद्योगों पर विचार करें तो देखेंगे कि प्रत्येक उद्योग के उत्पादन का आम आदमी की दैनिक आवश्यकताओं में स्थान है, और एक सामान्य जन किसी उद्योग के उत्पादन पर वार्षिक रूप से कितना खर्च करता है, उस उद्योग के सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन करने का यह एक मार्ग हो सकता है। जन साधारण के उपयोगार्थ विभिन्न उद्योग निम्न भिन्न-भिन्न उत्पादन उपलब्ध करवाते हैं (१) अन्न और धान प्रशोधन—चावल, (२) गुड़-खाण्डसारी—गुड़ और खाण्डसारी, (३) ताड़-गुड़-गुड़, (४) ग्रामीण तेल—तेल, (५) मधु-मखाना-जट्टा, (६) ग्रामीण चर्म—चर्म-उत्पादन, (७) आखाद तेल और माबुन—माबुन, (८) हाथ

कागज—कागज, (९) ग्रामीण कुम्हारी—वर्तन, (१०) गेशा—रस्सी तथा अन्य गेशा उत्पादन, और (११) बढईगीरी और लुहारगीरी—काष्ठ तथा लोहे के उपकरण आदि।

पारिवारिक बजट में स्थान

उन चीजों पर एक सामान्य नागरिक अपने परिवार के बजट में से कितना प्रति शत खर्च करता है, इस सम्बन्ध में कमीशन का आर्थिक अनुसंधान निर्देशालय सर्वेक्षण कर सकता है अथवा किये गये सर्वेक्षणों में आँकड़े प्राप्त कर सकता है। निश्चय ही इन आँकड़ों के सम्बन्ध में एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्नता मिलेगी और एक वर्ग में दूसरे वर्ग के आँकड़ों में तो यह भिन्नता काफी अधिक होगी, लेकिन इन आँकड़ों से एक आधार का निर्धारण तो आसानी से किया ही जा सकता है।

इन उद्योगों के विकामार्थ धनराशि का बटन करने के लिए एक वैज्ञानिक कमीटी हो, इस दृष्टि से पारिवारिक बजट में उनके सापेक्षिक स्थान के अलावा इन उद्योगों के निवेश-उत्पादन-अनुपात को ध्यान में रखना भी आवश्यक होगा। मरजाम, भयन तथा पशु-धन जैसे अनावर्ती और कच्ची सामग्री के भाण्डारीकरण, श्रमिकार्ड तथा विश्री जैसे आवर्ती खर्च एक से दूसरे उद्योग में भिन्न होंगे। उदाहरणार्थ, ग्रामीण तेल उद्योग

में उत्पादन के लिए विनियोजन मान लो १०० रुपये हैं तो वह हाथ कागज उद्योग के विनियोजन से भिन्न होगा। प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में इस प्रकार के आकड़े तत्सम्बन्धी उद्योग के पिछले वर्षों के काम के आधार पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

तृतीय मूल्य निर्धारक कारक

उद्योग में काम पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उनके द्वारा किया जानेवाला उत्पादन इन उद्योगों के सापेक्षिक महत्व का तीसरा निर्धारक कारक होगा।

प्रत्येक उद्योग की वास्तविक सफलताओं से बिल्कुल अलग, उसके विकास की भावी सम्भाव्यता चतुर्थ कारक होगा। कमीशन की अनुसूची में ऐसे उद्योग हैं, सम्पत्ति के नये-नये स्रोतों का उपयोग करना जिनका उद्देश्य है, उदाहरण के लिए अखाद्य तेल और साबुन उद्योग को लिया जा सकता है, जो फिलहाल बेकार जा रहे अखाद्य तिलहनो के सग्रह को प्रोत्साहन देना है और इनका तेल साबुन बनाने के काम में लाता है। लोक कल्याण के लिए अनुपयोगित साधन-स्रोतों का उपयोग करने की

दृष्टि से ग्रामोद्योग कार्यक्रम में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देना वाछनीय है।

विभिन्न उद्योगों के लिए धन-राशि के बटन को वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करने के बाद उनका जो माप-क्षिक महत्व है उससे सलग्न करना वाछनीय होगा। किसी उद्योग का महत्व निम्न चार कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये

कसौटी

अ उद्योग द्वारा उत्पादित माल का सामान्य जन के पारिवारिक बजट में स्थान,

आ निवेश-उत्पादन अनुपात,

इ वास्तविक उत्पादन तथा रोजगारी, और

ई उत्पादन और रोजगारी की दृष्टि में उद्योग की सम्भाव्यता।

केवल इसी तरह ग्रामोद्योग देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई वास्तविक प्रभाव डाल सकेंगे।

जदौर २५ मई १९६४

हर व्यक्ति जानता है कि मनुष्य सदैव या स्वभावतः उन प्रेरणाओं से काम नहीं करता, जिनके बारे में वह पूर्ण सचेत है या जो उसे स्वीकार्य हैं। अचेतन की या अस्वीकार्य प्रेरणाओं से अतटुटि को छोड़ना निश्चय ही एक आँख बन्द करके चलने के समान है।

— इ. एच. कार ह्यूट इज हिस्ट्री, पविन बुक्स, लंदन; १९६४।

टीका-टिप्पणी:

सहकारी प्रशासन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

तृतीय पंच वर्षीय योजना ने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में सहकारी विभाग के निरंतर विकास की परिकल्पना सही ही की है। अब तक इन तीन योजनावधियों के अन्तर्गत सहकार आन्दोलन में बड़ी मार्के की प्रगति हुई है और अब हमने वह रूप धारण कर लिया है कि निजी विभाग और सरकारी विभाग दोनों का ही ध्यान हम ओर जायेगा ही। अब यह अपने पैर जमा रहा है और निकट भविष्य में ही राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में इन दोनों विभागों में से किसी के भी समकक्ष स्थान प्राप्त कर लेगा। यह आन्दोलन जोकि कुछ वर्ष पूर्व तक मुख्यतः कृषकों को ऋण देने तक सम्बन्धित था, दिनोदिन विविध आर्थिक गतिविधियों को अपनाये जा रहा है और सरकार अब सहकार को समाज कल्याण सम्बन्धी नीति और समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिए उपयोगी माध्यम समझती है।

योग्य प्रशासन अत्यावश्यक

सहकारी विभाग के इस प्रगतिशील विकास ने कई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं, जिनमें से एक प्रमुख समस्या सहकारी समितियों के प्रशासन की है। एक समय था जबकि सहकार आन्दोलन के लिए व्यय के तौर पर यह कहा जाता था कि इसमें प्रशासन अधिक और वित्त कम है। अब ऐसी बात नहीं है और इसका सबूत है सहकारी प्रशासन सम्बन्धी समिति का गठन। प्रशासन की जिम्मेदारियाँ सहकार के अचानक विकास से बहुत ही जटिल और विविध हो गयी हैं और सहकार से सम्बन्धित प्रशासनिक पद्धति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इन तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए ही समिति की नियुक्ति की गयी है।

समिति ने देश में सहकारी प्रशासन पद्धति के कई पहलुओं पर विचार किया है तथा पद्धति को अभिनव और मजबूत बनाने तथा उसकी क्षमता को व्यापक बनाने के लिए कई सिफारिशें की हैं।

भूतकाल में सहकार आन्दोलन को गैर-सरकारी बनाने के विषय में बहुत विचार किया गया और अधिकांश लोग इस बात से सहमत हुए कि आन्दोलन को धीरे-धीरे गैर-सरकारी बना दिया जाना चाहिये। इस दृष्टि से पहली नजर में तो यह विरोधाभास ही लगेगा कि समिति ने सहकारी प्रशासन के विस्तार और उसकी मजबूती के लिए प्रस्ताव क्यों किये हैं। सहकार आन्दोलन की वर्तमान अवस्था का सूक्ष्म विवेचन करने से इस विरोधाभास की सहज ही व्याख्या हो जाती है। कटु सत्य तो यह है कि सहकार आन्दोलन अपनी सभी गतिविधियों में अथवा देश के सभी भागों में एकमन नहीं बढ़ा है। चूंकि अभी यह विकसित ही हो रहा है, अतः उचित ढंग से तथा योजना में परिकल्पित गति में विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और योग्य प्रशासनिक सठगन का होना आवश्यक है। स्वभावतः इसके लिए विकासशील और उपयोगी प्रशासन की जरूरत होगी, जोकि सहकारी कानून को कार्यान्वित करे। इसके साथ ही आन्दोलन के लिए स्वाभाविक नेतृत्व अथवा जन-नेतृत्व को भी विकसित होना है और उसके विकास को भी प्रोत्साहन देना है ताकि बाद में यह नेतृत्व पूर्णरूपेण इस प्रशासन तंत्र का स्थान ले सके।

हस्तक्षेप अप्रिय

समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि "सहकारी विभाग के आकार में किसी भी वृद्धि में सहकारी मस्थाओं

के दैनिक कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, जोकि उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर बुरा प्रभाव डाले। इसके विपरीत हमेशा यह कोशिश की जानी चाहिये कि यह आन्दोलन जन-आन्दोलन बन जाय।” समिति के ही शब्दों में “सहकारी प्रशासन की योग्यता अन्ततः सभी किस्म और सभी स्तर की सहकारी संस्थाओं के ठोस प्रबन्ध पर निर्भर करती है। इन समितियों के संचालकों में नेतृत्व की सही भावना आ जाने तथा सरकार से आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर लेने पर ही सस्थाएँ प्रगति कर सकती हैं। अतः हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जहाँ गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं का बड़ा संगठन हो, जोकि आन्दोलन के निर्माण में रुचि लेता और इस पर पूरा ध्यान देता हो, वहाँ सहकारी विभाग का प्रशासन अधिक कठिन नहीं होता और थोड़े से कर्मचारियों के जरिये भी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है।” तत्काल की मुख्य आवश्यकता है इस नेतृत्व को जिम्मेदारियों सम्भालने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि उत्तरदायित्व को सतोषजनक ढंग से निभाने से ही सहकारी आन्दोलन जीवन्त और स्वस्थ बन सकता है।

स्वावलम्बी आन्दोलन की ओर

आन्दोलन के चन्द ऐसे अंग भी हैं जहाँ कि सहकारी समितियों ने विकास की वह अवस्था प्राप्त कर ली है कि उन्हें वाहरी मदद, संरक्षण अथवा मार्गदर्शन की

आवश्यकता नहीं है। इन समितियों को सहकार कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप सहकारी प्रशासन के विभिन्न वैधानिक अथवा अन्य नियंत्रणों से धीरे-धीरे मुक्त किया जा सकता है। मिद्वान्त रूप में जबकि सभी यह स्वीकार करते हैं कि सहकार आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य स्वावलम्बी आन्दोलन बनना होना चाहिये, जोकि विना किसी वाहरी मदद के आगे बढ़ सके, वहाँ यह भी मानना ही चाहिये कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में काफी समय लग जायगा—सम्भवतः एक पुश्त अथवा उसमें भी अधिक। कारण स्पष्ट है। अतः हमें तथ्यों का सामना करना ही चाहिये तथा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का स्वागत करना चाहिये, जोकि सहकार विभाग के ठोस विकास के हित में ही है। सहकार आन्दोलन की अन्तिम सफलता विकास की ऐसी अवस्था प्राप्त करने में ही होगी, जबकि सरकार द्वारा उपलब्ध सहकारी प्रशासन आवश्यक नहीं रहेगा। अभी तो वर्तमान सहकारी प्रशासन को अपने को मजबूत और विस्तृत तथा अपनी गतिविधियों को अभिनव बनाना ही चाहिये, ताकि यह अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की उत्तम और मजबूत अवस्था में आ सके।

इसे दृष्टि में रखते हुए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों और संस्थाओं को समिति की सिफारिशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और कार्यान्वयन करना चाहिये।

—एन बाय. खेर

पूना. १५ जुलाई १९६४

गोबर गैस सयंत्र • एक अध्ययन

यह अध्ययन* पाठकों में गलतफहमी पैदा कर सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में मैं कुछ स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। मैंने उक्त सयंत्र को उस वक्त देखा था, जबकि मरम्मत होने के बाद उसमें तुरन्त ही गोबर घोंग भर गया था।

*बादी ग्रामोद्योग के जुलाई १९६४ अंक में एस डी तेज-नारायण और राम मूर्ति द्वारा लिखा गया लेख ‘गोबर गैस सयंत्र एक अध्ययन’।

वह सयंत्र तीन वर्ष पहले नयी दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था से प्राप्त नमूने के आधार पर बनाया गया था। दो वर्ष तक वह काम करता रहा और दूसरे वर्ष के उत्तरार्ध में गैस उत्पादन कम होता गया और अन्ततः बन्द हो गया। जब सयंत्र खोला गया तो पाचित्र के अन्दर भरे पदार्थ की सतह पर आधे गोबर की बहुत ही मोटी परत पायी गयी। मैंने जब सयंत्र देखा था तो उस समय उसे चलाना आरम्भ ही किया

गया था। गोबर धोल भरने के बाद सयत्र से आधे इंच व्यास की नली ग्राम सेविकाओं के कमरों तक ले जायी गयी। पाया गया कि वह नली एक साथ दो चूल्हों (बर्नर) के लिए पर्याप्त गैस नहीं दे सकी।

गैस-घर के बाहर तीन रिंग के सहारे तीन पाइप लगाये गये थे जिनमें गैस घर धीरे से छूने अथवा हवा के हल्के झोंके से भी करीब नौ इंच तक मुड़ जाता था। अतः गैस घर के गिरने से गैस के उपयोग के सम्बन्ध में विचार करना यदि असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है।

एक ओर आपत्ति है। गैस घर लगातार पाचित्र में गैस प्राप्त करता है। गैस प्राप्ति की दर अल्पावधि के लिए भी समान नहीं है।

एक आपत्ति यह भी है कि गैस घर का तापमान मुबह में बढ़ जाता है और शाम में घट जाता है। गैस की मात्रा तापमान में प्रति दस डिग्री घट-बढ़ के साथ तीन प्रति शत तक घट-बढ़ सकती है।

प्रस्तुत गैस घर पाँच इंच व्यास का है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है वह नौ इंच तक किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। चूँकि गैस घर की एक फुट ऊँचाई १६४ घनफुट गैस रखती है, इसलिए कम मात्रा की गैस के पर्यवेक्षण में जो गलतियाँ होंगी वे प्रयोगावस्था में दृष्टि ओझल कर दे सकनेवाली भूलों की सीमा में अधिक होंगी। इस बात को प्रयोगकारों ने यह कहते हुए माना है कि उनकी प्रति घंटा खपत के आकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।

स्पष्टीकरण की आवश्यकता

लेख में कुछ और बातें भी ऐसी हैं जिनके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है। बताया गया है कि पाचित्र की क्षमता १०० घनफुट धोल रखने की है। यह गुरु में दिये गये पाचित्र के माप के अनुसार नहीं है, जिसके मुताबिक यह क्षमता २०० घनफुट से भी अधिक आती है। लेखकों ने कहा है कि सयत्र की टंकी “१२०

पौण्ड गोबर में उतना ही पानी मिला कर भरी जा सकती है।” वे सम्भवतः उस मान का जिक्र करते हैं जोकि सयत्र में नित्य डालते हैं। इतना स्पष्ट देखा जा सकता है कि २४० पौण्ड गोबर और जल मिश्रण सिर्फ ३ घनफुट जगह को ही घेरेंगे क्योंकि एक घनफुट में ६८ पौण्ड गोबर धोल आता है।

बताया गया है कि प्राचार्य को यह मुझाव दिया गया कि इस गैस प्रदायक नलिका की जगह पोलिथिन लगी नलिका लगायी जाय “ताकि धातु नलिका होने तथा इसके जमीन के अन्दर होने से ताप और दबाव में जो अन्तर आ जाता है वह न आये और यह अधिक समय के लिए स्थानीय जलवायु ग्रहण करने योग्य बन सके।” ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन के अन्दर बैठायी गयी गैस प्रदायक नलिका की जगह जमीन के ऊपर पोलिथिन लगी नलिका लगायी गयी है। समझ में नहीं आता कि गैस का दबाव महज नलिका के द्रव्य को बदल कर इस प्रकार कैसे बदला जा सकता है। गैस का दबाव मुख्यतः प्रति घंटा गैस की प्रवाह नलिका के व्यास और नलिका की लंबाई से प्रभावित होता है। जहाँ तक तापमान ग्रहण करने का सवाल है जमीन के ऊपर बिछी नलिका स्वभावतः जमीन के अन्दर बिछी नलिका से बाहरी तापमान से अधिक प्रभावित होगी।

बताया गया है ६ व्यक्तियों के लिए तीन से चार घंटे में १३ से १५ घनफुट गैस की खपत होती है, परंतु इन आकड़ों में जिम निष्कर्ष पर पहुँचा गया है वह नहीं निकलता। इसके विपरीत इस प्रतिवेदन के आधार पर महज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस प्रकार भोजन पकाने के लिए ६ व्यक्तियों के परिवार हेतु प्रति दिन ५० से ६० घनफुट गैस उत्पादन पर्याप्त होगा। चूँकि एक समय, मुबह अथवा शाम, भोजन पकाने में ३० घनफुट से अधिक गैस का इस्तेमाल नहीं होता, अतः इससे कहीं छोटे गैस-घर में काम चल जाना चाहिये।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक द्वय केन्द्रीय सामुदायिक विकास, पंचायत राज और सहकार मंत्री श्री सुरेन्द्र कुमार डे के प्रश्नों का मान्य उत्तर प्राप्त करने के लिए यदि इस सयत्र पर फिर से परीक्षण

करे तो वे गोबर गैस सयत्र कार्य में बहुत सहायक सिद्ध होंगे।

— जशभाई झ. पटेल

बम्बई ११ जुलाई १९६४

उत्तर प्रदेश में गुड़ के संग्रह की समस्याएँ

संग्रह का कार्य है माल को उत्पादन के समय से लेकर उपभोग के वक्त तक भाडारित और परिरक्षित रखना। चकि उत्पादन और उपभोग साथ-साथ शायद ही कभी होते हैं, उत्पादक के पास से उपभोक्ता तक पहुँचने में माल को एक अथवा अनेक जगह संग्रह किया ही जाना चाहिये। संग्रह की आवश्यकता मूलतः इसलिए पड़ती है कि माल के उत्पादन और उपभोग काल के बीच समजन नहीं होता। इसका मुख्य कार्य है यह समजन लाने के लिए माल का संग्रह करना। बिक्री कार्य में संग्रह से काफी सहायता मिलती है। व्यवस्थित बिक्री की प्रगति में यह एक महत्वपूर्ण सोपान है। संग्रह से होनेवाले लाभों का चित्र व्यापार, वाणिज्य और उद्योग तथा अन्ततः समाज को होनेवाले लाभों के अध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा। उनका सार यहाँ दिया जा रहा है।

संग्रह के लाभ

१. **मौसम और पूर्ति का समजन** - एक मौसम में उत्पादित माल का इस्तेमाल यदि दूसरे मौसम में करना है तो उसका संग्रह करना ही होगा। अधिकांश कृषि उत्पादनों के मामले में यही होता है। अस्थायी बाजार अवस्थाओं और मौसम तथा पूर्ति सम्बन्धी लघु-काशीन समस्याओं के कारण भी माल-संग्रह आवश्यक बन जाता है। इस प्रकार यदि नाशवान पदार्थों की बाजार में अस्थायी भरमार है तो उन्हें कीमत सुधरने तक कुछ दिनों के लिए ही भाडारित किया जा सकता है।

२. **अतिरिक्त-कमी-समीकरण** एक बाजार के अतिरिक्त माल को तब तक संग्रहीत किया जा सकता है जब तक कि उसका इस्तेमाल न हो जाय अथवा वैसे बाजार में भेजने की परिवहन सुविधाएँ न मिल जायें जहाँ से अच्छे पैसों मिलने की उम्मीद हो।

३. **अन्य बिक्री कार्यों में सुविधा** : अन्य बिक्री कार्यों के लिए भी संग्रह अत्यावश्यक है। जैसे, माल तब तक एकत्रित किया जा सकता है जब तक कि ट्रक-भर अथवा गाड़ी भर सामान न हो जाय।

४. **तकनीकल संग्रह** संग्रहीत माल के नमूने खरीदारों को दिखाये जा सकते हैं और उनका निरीक्षण, वर्गीकरण, मफाई, पैकिंग और वजन किया जा सकता है।

५. **समपाद्वर्ष सरक्षण** : संग्रहीत माल का उपयोग ऋण के लिए समपाद्वर्ष रूप में भी किया जा सकता है।

६. **मूल्य स्थिरीकरण** और, अन्ततः, संग्रह का बाजार मूल्य से सम्बन्ध भी महत्वपूर्ण है। जखरत से बहुत अधिक माल जमा हो जाने पर प्रायः मूल्य में कमी आ जाती है। यदि माल भाडारित किया जा सकता है तो मूल्य भी स्थिर किये जा सकते हैं और माल रखनेवाले के नुकसान को, उसे बाद में ऊँची कीमत पर बेच कर, कम अथवा दूर किया जा सकता है।

योग्य संग्रह के लिए, जोकि सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त लाभ पहुँचा सकता है, यह अत्यावश्यक है कि माल की उचित देख-भाल की जाय, सहज स्थलों पर भाडारित किया जाय और संग्रह कार्य इस तरह नियन्त्रित किया जाय कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के हित की रक्षा हो सके।

अब हम यह देखें कि विभिन्न स्थानों में गुड़ का संग्रह कैसे किया जाता है, यह सेवा कितनी योग्य है तथा इसे और योग्य बनाने के लिए कौन-कौन-से सुधार सुझाये जा सकते हैं।

ग्राम स्तर पर

गुड़ उत्पादक उत्पादन का २० से २५ प्रतिशत अपन पास रख कर बाकी मडियों में व्यापारियों को बेच देते

हैं। भारतीय किसानों की जो अवस्था है, उसमें वे गुड़ का सग्रह हाडियों में करते हैं, जिनका मुहडक्कन अथवा कपड़े से बन्द रखते हैं या खोई अथवा भूसे की चटाई पर उसका कोठा बना कर रखते हैं। अच्छी आर्थिक अवस्थावाले चन्द किसान गुड़ को अपने ही घरों में कोठा बना कर अथवा मिट्टी की हाडियों में उनका मुह मिट्टी-भूसी से बन्द कर रखते हैं।

गुड़ में बहुत जल्दी नमी आ जाती है। ग्रामीणों के कच्चे घरों में वागिन से अधिक बचाव नहीं हो पाता। फिर, कच्चे घरों के कच्चे फर्श भी नम हो जाते हैं, जोकि गुड़ के लिए अच्छा नहीं है। यही कारण है कि किसान गुड़ तैयार करने के बाद गांव में ही पहला मौका पाते ही, सिर्फ ५-७ प्रति शत घरेलू उपयोग के लिए रख कर, बेच देते हैं। गांव में गुड़ का सग्रह न होने अथवा खराब सग्रह होने का एक मुख्य कारण है दोषपूर्ण स्थान होने में अनार्थिक सग्रह।

मण्डी स्तर पर

उत्पादन का अधिकांश भाग मौसम में मंडी में चला आता है। कच्चे और पक्के आढतिये स्टोक जमा करने के लिए बड़ी मात्रा में गुड़ खरीद लेते हैं। उसे वे बोरो में अथवा खुले में एक पर एक गुड़ की चक्की रख कर सग्रह करते हैं। इस तरीके से ४० से ५० किलोग्राम की क्षमतावाले बोरो में गुड़ भर कर उनका मुह सी देते हैं और उन बोरो को गोदाम में एक के ऊपर एक लाद देते हैं। इन गोदामों की क्षमता १०० से ५०० क्वीटणल गुड़ रखने की होती है। आम तौर पर ये गोदाम आवास स्थल हुआ करते हैं, जिनका मौसम में गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतया गुड़ को चटाई पर फेला देते हैं ताकि उसमें नमी न आये। इन गोदामों का भाड़ा ४० से ५० किलोग्राम के १०० कट्टे के लिए १० से १२ रुपये है, जोकि कोठा कितना सुरक्षित है उस पर निर्भर करता है।

इन गोदामों का उपयोग मितव्ययी होता है, क्योंकि सिर्फ भाड़ा देना होता है और वह भी सिर्फ मौसम के लिए। आढतियों को सामान्यतया पूरा विश्वास होता

है कि उन्हें वे स्थान मिल ही जायेंगे, क्योंकि उनका सिवाय गोदाम के और कोई उपयोग नहीं हो सकता। परन्तु अवस्था उतनी लाभप्रद नहीं है जितनी दिखाई देती है। इस तरह के सग्रह में एक बड़ा नुकसान यह है कि यदि दो-तीन महीने से अधिक गुड़ को रखा गया तो वह धीरे-धीरे छोआवनने लगता है, जिससे उसका स्तर गिर जाता है। इस मौसम में प्रति बोरा तीन से पाँच किलोग्राम का नुकसान हो जाता है।

खुले में रखने की पद्धति

इस पद्धति के अन्तर्गत मंडी में दुकानों के अन्दर फर्श पर गुड़ की भेलियों को एक के ऊपर एक करके चार पाँच भेली रखते हैं। नमी से बचाने के लिए पहले तरीके की तरह ही यहाँ भी फर्श पर चटाई बिछा देते हैं। इन भेलियों को फिर तारपोलीन अथवा चटाई या मोटे कपड़े से ढक देते हैं। इस तरह का सग्रह बुलन्दशहर जिले की सिर्फ मियाना और गुलोती मंडियों में ही होता है। भाड़ा प्रति ५० क्वीटणल पाँच से सात रुपये होता है। यहाँ एक बड़ा लाभ यह है कि बरसात के दिनों को छोड़ कर, जबकि आर्द्रता अधिक होती है, बाकी दिनों में गुड़ अनुकूल जलवायु होने के कारण सूखा रहता है।

हर मंडी की सग्रह-क्षमता भिन्न होती है। सामान्यतया बड़ी मंडी की क्षमता बड़ी और छोटी मंडी की छोटी होगी, परन्तु, सब जगह ऐसा नहीं है, जैसे, मियाना छोटी मंडी है परन्तु उसकी सग्रह-क्षमता एक लाख क्वीटणल गुड़ है। गुलोती मंडी के साथ भी वही बात है।

सामान्यतया गुड़ जनवरी से जून तक सग्रह किया जाता है, परन्तु चन्द मंडियों में, जहाँ कि जलवायु अनुकूल है और अवस्थाएँ अच्छी हैं, अक्तूबर में नये मौसम के आरम्भ तक सग्रह करते हैं। अक्तूबर और नवम्बर माह से ही गुड़ के सग्रह न करने का कारण यह है कि बाजार में पहले-पहल जो गुड़ आता है वह सग्रह करने लायक नहीं होता। पके गन्ने के रस से जो गुड़ तैयार किया जाता है, वही कुछ दिनों तक सग्रह कर रखा जा सकता है।

प्रत्येक मंडी में सग्रह खर्च २० मे २५ पैस प्रति बोरा बैठता है। सग्रह खर्च में ये मद शामिल हैं माल लदाई-

तीन पैसे, गाड़ी दुलाई—तीन पैसे, चटाई—दो से तीन पैसे, थपी लगाई—तीन पैसे, भाड़ा—छ से दस पैसे, और बीमा—दो से तीन पैसे, कुल—१६ से २४ पैसे।

अब हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह जाचने का है कि सग्रह कार्य कितना योग्य है। सग्रह की समस्या की छानबीन करने पर हम पाते हैं कि (१) ग्रामीण स्तर पर गड सग्रह की सुविधाएँ नहीं होती और जो भी सग्रह होता है वह अवैज्ञानिक, अपरिष्कृत और अनाधिक होता है, (२) गाँवों में बैकिंग और बीमा सुविधाएँ नहीं हैं जो कि किसानों को सग्रह कार्य अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे सकती हैं, (३) सड़कों की कमी अथवा उनका न होना और परिवहन एवं संचार माध्यमों की अयोग्यता के कारण गाँवों में माल सग्रह की बात सोची ही नहीं जा सकती और (४) पिछले दशक में आयोजकों और सरकार के प्रयत्नों के बावजूद किसानों की माली हालत नहीं सुधरी है और रुपये-पैसे सम्बन्धी उनकी जरूरतें उन्हें उत्पादन के बाद तुरन्त ही अपने माल बाजार में भेज देने को मजबूर कर देती हैं।

सग्रह योग्यता

(१) किसी भी किस्म की मडी में वैज्ञानिक ढंग से सग्रह कार्य नहीं होता, (२) उत्तर प्रदेश की प्रत्येक मडी में गुड खाण्डसारी व्यापारी सघ हैं, परन्तु उसने इस समस्या पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है, (३) सग्रह में होनेवाले नुकसान से बचने अथवा सग्रहीत गुड-खाण्डसारी का स्तर न गिरने देने के लिए वर्तमान कोठाओं अथवा गोदामों की अवस्था सुधारने हेतु भी कीटनाशकों और अन्य रसायनों एवं सग्नजामों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और (४) सग्रह के तरीके भी नहीं सुधरे हैं।

कुछ समय से उत्तर प्रदेश गोदाम निगम ने चन्द मडियों में सग्रह कार्य अस्थायी आधार पर किराये पर

मकान लेकर आरम्भ किया है। इस गोदामों में स्तर को बनाये रखने और नुकसान रोकने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। सग्रह के लिए वे प्रति बोरा १२ से १५ पैसे लेते हैं।

अनुसंधान की आवश्यकता

गुड का सग्रह एक गम्भीर समस्या है, जिसका तत्काल हल निकालना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और बुलन्दशहर जिलों से बने मेरठ क्षेत्र की १२ मडियों में जमा स्टॉक के आधार पर एक मौसम में करीब एक लाख क्वींटल गुड के नुकसान का अन्दाज है। * जबकि गुड का सग्रह दिसम्बर-जनवरी में शुरू हो कर जन-जुलाई तक चलता रहता है और सग्रह में असल नुकसान अप्रैल-मई माह में आरम्भ होकर जन और जुलाई में बारिश शुरू हो जाने पर बहुत बढ़ जाता है।

विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं तथा विभिन्न अनुसंधान अभिकरणों द्वारा कई प्रयोग किये गये हैं। गुड उत्पादकों और इसके व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के समक्ष मुख्य समस्या 'सग्रह' ही है। गुड का रंग, स्वाद आदि बनाये रखने और सग्रह में कोई नुकसान न होने एवं सग्रह का तरीका सस्ता तथा उत्पादकों और बिचवानियों की पहुँच के अन्दर होने का पूर्ण आश्वासन देने के लिए निरन्तर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। उत्पादन और बिक्री के विभिन्न क्षेत्रों में, स्थानीय जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी की किस्म, स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धि तथा गुड के सग्रह को प्रभावित करनेवाले कारणों का ध्यान में रखते हुए, अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए।

—भारत भूषण कसाल

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ९ जुलाई १९६४

* यह अंदाज लेखक ने विभिन्न मडियों के आँकड़ों से हुई अपनी बातचीत के आधार पर दिया है। इन आँकड़ों के पाम अप्रैल से जुलाई माह तक करीब १५ में १० लाख

क्वींटल स्टॉक रहता है और प्रति क्वींटल ५ से ७ किलोग्राम नुकसान होने में मोठे तौर पर कुल एक लाख क्वींटल नुकसान हो जाता है।

जम्मू और कश्मीर का पशुधन : चन्द समस्याएँ

माखन लाल भट

जम्मू और कश्मीर राज्य में पशुपालन से ४०,००० लोगों को प्रत्यक्ष रोजगारी मिलती है और राज्य की कुल आय में उसका योगदान १५ प्रति शत है। अतिरिक्त मवेशियों की छटारें और उनकी सख्या में होनेवाली वृद्धि पर नियंत्रण करना आवश्यक है, विशेष कर इसलिए कि चरगाढ भूमि दिन ब दिन कम होती जा रही है। लक्ष्य होना चाहिये सूखी और बेकार गायों, अन्य बेकार मवेशियों तथा दूध देनेवाली गायों एवं अन्य उपयोगी मवेशियों के बीच उचित संतुलन स्थापित करना।

जम्मू और कश्मीर राज्य के सामाजार्थिक ताने-बाने में पशुधन का स्थान, रोजगारी और आमदनी दोनों ही मामलों में, कृषि के ही बाद आता है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब ४० हजार^१ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगारी देने के अलावा यह राज्य की कुल आय में करीब १५ प्रति शत योगदान देता है और इस उद्योग में हुई आय राज्य में कृषि से हुई आय के ३३ प्रति शत से अधिक होती है।^२ इसमें कृषि और परिवहन में वाहक के रूप में जिन वैल शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है वह शामिल नहीं है। पशु-पालन विभाग से होनेवाली कुल आय का ९० प्रति शत तो अकेले गोजातीय मवेशियों से ही होता है।

इसके बावजूद कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था को नव रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, राज्य की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में इस विभाग का वर्तमान महत्व तो आगामी १०-२० वर्षों में कम होने की आशा नहीं है, क्योंकि राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना के अवसर पर्याप्त बंधे खर्चों, उद्योग स्थल के लाभों की कमी और प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के कारण बहुत कम ही हैं। परम्परागत दस्तकारियों की भांति बराबर कमी होते जाने और

विभिन्न ग्रामीण उद्योगों के धीरे-धीरे नष्ट हो जाने में, जिनमें अब तक राज्य के बहुत-से ग्रामीणों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगारी मिलती थी, भी कृषि विभाग का महत्व बढ़ गया है जिसका पशुपालन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके अतिरिक्त वर्तमान कृषि व्यवस्था के अन्तर्गत कई कृषि प्रक्रियाओं के यात्रीकरण की संभाव्यता, जोकि अभी पशुओं की मदद से की जा रही है, कई वर्षों तक सीमित ही रहेंगे।

पशुधन के आकार का नियमन

ऐसी परिस्थितियों में वाहन के काम आनेवाले बेलों के साथ ही दुधारू मवेशियों का बड़ी संख्या में हाना-बर्तों कि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त चारा हो-एक सम्पत्ति ही है। दुर्भाग्यवश राज्य में चारे की अवस्था अच्छी नहीं है। कठिनाई मवेशियों की कमी की नहीं है—बल्कि उनकी संख्या तो इतनी अधिक है कि वह एक गंभीर समस्या पैदा कर देती है जोकि इससे और भी गंभीर हो जाती है कि उनकी नस्ल अच्छी नहीं है—उनका रखना अनर्थिक है तथा वे कमजोर भी हैं। इस प्रकार मवेशियों की संख्या का अविकाश एक महान राष्ट्रीय सम्पत्ति

१. देखिए जनगणना १९४१। सन् १९६१ के लिए दिये गये आंकड़े बाधकलित हैं।

२. राज्य के सांख्यिकीय विभाग द्वारा तैयार किया गया एंस्टि-मेट्स ऑफ स्टेट इनकम ऑफ जम्मू खण्ड कश्मीर

स्टेट देमिण्ड। पशुधन से होनेवाली आय को कम अंदाज कर बताया गया है, क्योंकि इसमें मांस, हार्दियों, चर्बा, रींग, घुर आदि से होनेवाली करीब ४० लाख रुपये की अनुमानित आय शामिल नहीं है।

हाने के बदले राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ बन गया है। अतः यह अनिवार्य है कि उनकी सख्या को कम व नियमित करने और साथ ही हल चलाने लायक बैलो तथा दुधारू मवेशियों की नस्ल उन्नत करने की व्यवस्था की जाय। अभी यह काम मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक ओर तो जानवरों का मारा जाना सख्त मना है और दूसरी ओर नियति पर भी प्रतिबन्ध है।^३ अनियन्त्रित पैदायश के कारण मवेशियों की मख्या बढ़ने से कमजोर और अवभूखे जानवरों की सख्या बढ़ती है, जोकि किसी भी बीमारी के जल्द ही शिकार हो सकते हैं।

उपर्युक्त समस्या को समझने और उसका हल निकालने के लिए रास्ता ढ़ाजने हेतु राज्य की मवेशी अर्थ-व्यवस्था के चन्द मुख्य पहलुओं को फिर से समझ लेना उपयुक्त होगा। सन् १९५६ की पशु-गणना^४ के अनुसार

प्रति शत रही। राज्य में मवेशियों की सख्या में अधिक वृद्धि हुई और भैंसों के मामले में यह सामान्य रही। प्रान्तवार कुल मवेशियों के आकड़े, सन् १९५१ और १९५६ दोनों ही वर्षों के लिए, नीचे तालिका १ में दिये गये हैं।

घनत्व

इस धारणा की पुष्टि कि राज्य की मवेशी आबादी बहुत बड़ी है, इस बात से हो जाती है कि प्रति एक सो हैक्टर कृष्ट क्षेत्र की गोजातीय आबादी २७ है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में २८ है, जहाँ कि इसका घनत्व सबसे अधिक है। इसी प्रकार राज्य में प्रति एक सौ व्यक्ति पीछे पशु आबादी ६९ है और इसमें इसका स्थान हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, जिनका अनुपात क्रमशः ९० और ७६ है, के ही बाद आता है। सम्पूर्ण देश में प्रति १०० व्यक्ति पीछे मवेशी आबादी ४० से अधिक नहीं है।

तालिका १

जम्मू और कश्मीर में पशुधन की सख्या

(लाख में)

	१९५१				१९५६			
	जम्मू	कश्मीर	लद्दाख	कुल	जम्मू	कश्मीर	लद्दाख	कुल
मवेशी	६ ७४	६ २०	० २०	१३ १४	९ ०२	८ ३४	० २०	१७ ५६
भैंस	२ ५१	० २७	—	२ ७८	३ ४१	० ३१	—	३ ७२
कुल	९ २५	६ ४७	० २०	१५ ९२	१२ ४३	८ ६५	० २०	२१ २८

गोजातीय मवेशियों की सख्या^५ सन् १९५१ की १५ लाख ९ हजार के मुकाबले २१ लाख २८ हजार थी अर्थात् पाँच साल में ३३ ७ प्रति शत वृद्धि यानी प्रति वर्ष ६ ७ प्रति शत अभिवृद्धि हुई। इसी अवधि में सम्पूर्ण देश में यह वृद्धि २ ५ प्रति शत^६ अर्थात् प्रति वर्ष ० ५

भैंसों के मामले में भी प्रति १०० हैक्टर पीछे भैंस की सख्या ५३ है और इसमें इस राज्य का स्थान आन्ध्र प्रदेश के ही बाद आता है, जहाँ कि भैंस-आबादी का सर्वाधिक घनत्व (प्रति १०० हैक्टर पीछे ५७ भैंस) है। अखिल भारत घनत्व प्रति १०० हैक्टर कृष्ट क्षेत्र पीछे ३४ भैंस

३ 'जम्मू और कश्मीर रणवीर दण्ड संहिता' के अन्तर्गत गोजातीय पशुओं के ऐच्छिक वध पर प्रतिबन्ध है। गोजातीय पशु निर्यात (प्रतिबन्ध) अधिसूचना १९५० के अन्तर्गत गोजातीय पशुओं का राज्य सीमा के बाहर निर्यात करना भी मना है।

४ राज्य के लिए पशु-गणना १९६१ के अन्तिम आकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। स्वभावतः विचार-विमर्श को १९५६ की पशु गणना के आकड़ों पर ही आधारित करना

पड़ा है। तथापि, १९६१ की पशु-गणना के अस्थायी आकड़ों के अस्थायी अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस लेख में हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे करीब-करीब सही ही हैं।

५ यहाँ मवेशी का अर्थ है गोजातीय पशु, जैसे, गाय, बैल, बकरी, भैंस, मैमा और उनके बच्चे।

६ सन् १९५१ की तुलना में १९५६ में अधिक वृद्धि पायी जाने का कारण यह है कि १९५०-५१ वर्ष में पशुधन की कोई नियमित गणना नहीं हुई थी। उस वर्ष के लिए आकड़ें

हैं और प्रति १०० व्यक्ति पीछे १२ भैंस। कर्पक और दुधारू दोनों ही किस्म के मवेशियों के मामले में सख्या का आधिक्य है।

कर्पक मवेशी

कुल आबादी २१ लाख २८ हजार में से कर्पक मवेशियों का प्रातिशत्य २५ है। काम आनेवाले मवेशियों की कुल आबादी में से करीब ९२ प्रतिशत बैल, ६ २ प्रतिशत भैंसे, ० ५ प्रतिशत गाय और १ ३ प्रतिशत भैंस हैं। काम आनेवाले पशुओं में मवेशियों का प्रातिशत्य ९५ है।^७ नर पशुओं के आधार पर भी अनुपात करीब-करीब बराबर ही है। तथापि, कुल कृष्ट भूमि का कुल कर्पक पशुओं के सन्दर्भ में प्रति जोड़ा बैल पीछे औसत भूमि करीब छ एकड़ है। सम्पूर्ण देश के लिए प्रति जोड़ा बैल पीछे १० एकड़ भूमि है और गुजरात के लिए तो १६ एकड़। इसे देखते हुए इस राज्य के लिए तो यह सख्या बहुत ही कम है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इस जलवायु और नम भूमि में एक जोड़ा बैल औसतन १० एकड़ भूमि जोत सकता है, यह प्रत्यक्ष है कि सम्पूर्ण राज्य में उत्कर्षण शक्ति आवश्यकता से कहीं अधिक है। इस प्रकार क्षमता के एक बड़े भाग का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। यह एक गम्भीर समस्या है, जिसके हल के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिये। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कर्पक मवेशियों पर कार्य-भार भी बहुत भिन्न है। सच तो यह है कि कश्मीर प्रान्त में बैलों पर अपेक्षित काम का अधिक बोझ है। यह विरोधाभासी स्थिति पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, जैसा कि तालिका २ से प्रदर्शित है।

षट्वासी स्तर पर प्राप्त किये गये थे। अतः फलस्वरूप कमअदाज की गुजाइश तो है ही। समय बीतने पर राज्य में राजनीतिक स्थिरता आने और आयोजित विकास के कारण राज्य की आर्थिक अवस्था में सुधार होने के फल-स्वरूप लोगों ने १९४७ में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशीश की है। इसका कुछ अंश १९५६ में पशु-गणना की पद्धति और संगठन में

तालिका २

काम आनेवाले मवेशी और कृष्ट क्षेत्र

(प्रति जोड़ा बैल पीछे कृष्ट भूमि)

(एकड़ में)

वर्ष	जम्मू	कश्मीर	कुल
१९५१-५२	५ ६	११ ०१	७ ४
१९५२-५३	४ ८	११ ००	६ ७
१९५३-५४	४ ८	१० ००	६ ५
१९५४-५५	५ ०	७ ८	६ ०
१९५५-५६	६ ३	७ २	५ ९
१९६०-६१	५ ९	८ ०	५ ८

दुधारू मवेशी

दुधारू पशुओं के सम्बन्ध में स्थिति, जोकि कुल गोजातीय आबादी के (जहाँ तक उनकी सख्या का सम्बन्ध है) ३८ ४ प्रतिशत है, सम्पूर्ण देश की तुलना में बड़ी प्रोत्साहक है। प्रति १०० व्यक्ति पीछे २३ दुधारू पशु हैं जिनमें २८ गाय और ५ भैंसे हैं जबकि सम्पूर्ण देश के लिए यह सख्या सिर्फ १८ है—१२ गाय और ६ भैंस। जम्मू प्रान्त में अपेक्षित दुधारू पशुओं की सख्या अधिक है, जबकि कश्मीर प्रान्त में चरागाह, जंगल और उपयुक्त आबहवा जैसी आवश्यक सुविधा होने पर भी लड़ाख से भी कम सख्या में पशु है। मुख्य कमी भैंसों के मामले में है।

सुधार की वजह में विशुद्ध सांख्यिकीय भी हो सकता है। ७ इस क्षेत्र में बैलों को प्राथमिकता दी जाती है। भैंस अथवा भैंसों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। यदि उनका कोई इस्तेमाल होता है तो वह राज्य के जम्मू प्रान्त तक ही सीमित है। धार्मिक और सामाजिक कारणों से गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

राज्य की पशु पाल्य अर्थ-व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी सख्या में दुधारू पशुओं का मिलना बड़ी अच्छी बात है बशर्ते कि इनमें से सब अथवा अधिकांश का उपयोग आर्थिक रूप में मुलझे हुए ढंग से, कुछ समय बाद ही सही, किया जाय।

परन्तु इसके विपरीत दुधारू पशुओं की रचना बहुत ही असंतुलित है। यहाँ तक कि कुल दुधारू पशुओं में दूध देनेवाली गाय और भैंस का अनुपात मुश्किल से

तालिका ३

प्रति एक सौ व्यक्ति पीछे तीन वर्ष से अधिक उम्रवाली दुधारू गायों की सख्या

प्रान्त	गाय	भैंस	गाय और भैंस
जम्मू	२८	१६	४४
कश्मीर	१५	१	१६
लद्दाख	१६	—	१६
कुल (जम्मू और कश्मीर)	१८	५	२३

२६ प्रति शत है, जबकि सूखी और विशेष कर 'बेकार' दुधारू मवेशियों का क्रमशः ५० और १५ प्रति शत है। इससे एक ओर तो दूध देनेवाली गायों की कमी परिलक्षित होती है जिससे कि बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, और दूसरी ओर यह ज्ञात होता है कि अनाधिक मवेशियों की सख्या कितनी अधिक है। देश के प्रमुख भागों में भी, जोकि सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए जम्मू और कश्मीर के समान ही या उसमें भी गयी बीती विकासा वस्था में है, दूध देनेवाली गायों का अनुपात काफी ऊँचा है। सम्पूर्ण देश के लिए भी बेकार मवेशियों की सख्या में, जिनका उपयोग न किसी काम में किया जाता है और न ही अभिजनन के मामले में, कमी हुई है। तालिका ४ से यह बिल्कुल स्पष्ट है।

सूखे और बेकार मवेशियों का आधिक्य होने से, जोकि उपलब्ध चारे का अधिकांश खा जाते हैं, दूध देनेवाली गायों को पूरा चारा नहीं मिल पाता और स्वभावतः वे दूध कम देती हैं। औसतन एक गाय एक दिन में १३ पौण्ड से दो पौण्ड दूध देती है और इस आधार पर सालाना २७ लाख मन दूध का उत्पादन होता है। इसका अर्थ है प्रति व्यक्ति पीछे प्रति दिन २ ४ औंस दूध की पूर्ति जबकि मानक आवश्यकता १० औंस दूध की है। ग्रामीण आबादी तो सामान्यतया और भी कम दूध का सेवन करती है, क्योंकि अधिकांश दूध से घी निकाल कर महाजनो को दे दिया जाता है अथवा कर्ज चुकाने में चला जाता है अथवा कभी-कभी बेच दिया

तालिका ४

विभिन्न राज्यों में दूध देनेवाले तथा सूखे मवेशियों का तुलनात्मक अध्ययन (प्रातिशत्य)

राज्य	दूध देनेवाले	सूखे	बेकार	कुल
पंजाब	५९	३५	६	१००
असम	५५	२५	२०	१००
मध्य प्रदेश	४२	४६	१२	१००
हिमाचल प्रदेश	४२	४९	९	१००
उत्तर प्रदेश	४१	५०	९	१००
आन्ध्र प्रदेश	३९	४४	१७	१००
जम्मू और कश्मीर	२६	५९	१५	१००
अखिल भारत	४०	४३	१७	१००

जाता है। तथापि, तर्क सगत आधार पर राज्य को प्रति वर्ष वर्तमान आबादी के लिए प्रति व्यक्ति १० औंस की दर से एक करोड़ मन दूध की जरूरत है। इसकी प्राप्ति चन्द ऐसे सुधार करने में हो सकती है, कि गाय का औसत उत्पादन कम से कम छ पौण्ड बढ़ जाय और भैंस का नौ पौण्ड। इसकी प्राप्ति के लिए हमें अनाधिक और बेकार मवेशियों को दूर कर देना है जोकि

कुल दुधारू मवेशियों के तीन-चोथाई हों और उनकी जगह ऊँची नम्ल के मवेशी ले आने हैं। अधिकांश देशों में जहाँ कि पशुपालन जम्मू और कश्मीर की तरह ही महत्वपूर्ण है और विशेष कर उन क्षेत्रों में जहाँ कि दुग्ध उद्योग बहुत ही विकसित है, दूध देनेवाले पशुओं की संख्या सूखे पशुओं से ज्यादा है और सूखे पशुओं की संख्या पर अर्थ-व्यवस्था की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण किया जाता है।

बैलों की संख्या गायों से कम

एक महत्वपूर्ण बात और। राज्य में बैलों की संख्या गायों से कम है जैसा कि भारत में कहीं नहीं है। सन् १९५६ की पशु-गणना के अनुसार गायों की संख्या ८ लाख २२ हजार और बैलों की संख्या ५ लाख ४१ हजार थी। इस प्रकार गायों की संख्या बैलों से ७० प्रति शत अधिक है। अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि प्रति बैल पीछे डेढ़ गाय थी। इसके विपरीत संपूर्ण भारत में प्रति गाय पीछे करीब १ ३ बैल है। कई राज्यों में तो यह अनुपात १ ५ से भी ज्यादा है। बैलों और गायों के संख्या में अन्तर इस कारण है कि स्वाभाविक रूप से बैल का मृत्यु अनुपात अधिक है। गाय और बैल के बीच गायों की जरूरत मुख्यतः बैलों के प्रजनन के लिए है और दुग्ध उत्पादन तो अधिकांश किसानों के मामले में प्रासंगिक भर है। कर्पक कार्य योग्यता के साथ किया जाय, इसके लिए जरूरी है कि बैलों को पर्याप्त चारा दिया जाय। स्वभावतः उपलब्ध भोजन पहले बैल को मिलता है और फिर बचा-खुचा गायों को। खुराक और रख-रखाव में इस अन्तर के कारण बैलों की संख्या गायों से कम नहीं होनी चाहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं है। अतः यह माना जा सकता है कि बैल अधिक कार्य भार होने की वजह से अधिक संख्या में मरते हैं।

इस पर हम कुछ और सूक्ष्म रूप से विचार करें। सन् १९५६ में विभिन्न आयु वर्ग की गायों और बैलों का वितरण तालिका ५ में दर्शाया गया है।

निम्न तालिका से यह जाहिर है कि ०-१ और १-३ आयु वर्ग में गायों और बैलों की संख्या करीब-करीब समान है, जिससे यह पता चलता है कि इस अवस्था में इन दोनों श्रेणियों के बीच कोई विभेद अथवा चुनाव नहीं होता। परन्तु अगले आयु वर्ग में अर्थात् तीन वर्ष और उसमें ऊपरवाले वर्ग में गायों की संख्या बैलों की संख्या से करीब ५२ प्रति शत अधिक है। यह अखिल भारत पद्धति से बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कि बैलों की संख्या गायों की संख्या से २५ प्रति शत अधिक रहती है।

तालिका ५

सन् १९५६ में जम्मू और कश्मीर में विभिन्न आयु वर्गों की गायों और बैलों का वितरण (लाख में)

आयु वर्ग (वर्ष)	बैल	गाय	कुल
०-१	१ ४८	१ ७१	३ १९
१-३	१ ९७	२ ५२	४ ४९
३ और अधिक	५ ४१	८ २२	१३ ६३
कुल	७ ८६	१२ ४५	२१ ३१

यह इस बात का सूचक है कि बैलों के विपक्ष में कोई निश्चित चयन-प्रणाली कार्य कर रही है अथवा गायों का जन्मानुपात अपेक्षतया अधिक है। बादवाली बात अधिक जचती है, क्योंकि हम यह आशा नहीं कर सकते कि किसान बैल, जोकि उसकी खेती का मुख्य साधन है, की अपेक्षा गाय पर ज्यादा ध्यान देगा अथवा उस पर ज्यादा खर्च करेगा। यह हो सकता है कि छोटी जोतवाले किसान, जोकि सामान्य आय कमानेवाली फसलें ही उगाते हैं, अपने बैलों की बीमारियों से रक्षा करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपलब्ध न कर सकें, जिसका परिणाम यह निकलता है कि उनमें से अधिकांश पशु कुसमय और अस्वाभाविक मौत मर जाते हैं।

ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बूढ़े तथा अनुत्पादक बैल ही भूख मरने हो बल्कि युवा मवेशियों के अधिकांश को भी वही भुगतना पड़ता है। सामान्यतया एक गाय को अपनी उत्पादक उम्र में, यदि उसे दूध देना होता है तो, कम से कम ८ बछड़े पैदा करने होते हैं, जिससे गायों की शक्ति तो क्षीण हो ही जाती है, साथ ही उनकी सख्या किमान की ज़रूरत से भी अधिक हो जाती है—एक निश्चित सख्या में पाले अथवा बदले जानेवाले मवेशियों में भी अधिक। वस्तुतः प्रति गाय में दो अथवा तीन बछड़ों की पैदाइश निश्चित स्तर पर पशुधन बनाये रखने के लिए पर्याप्त होगी, जोकि फिर भी अधिक है। बाकी अतिरिक्त है और उन्हें छाट कर निकाला ही जाना चाहिये, जिसकी इजाजत किमानों को नहीं है।

उच्च मृत्यु अनुपात

अतः वह नजरअन्दाज और भूख का रास्ता अपना उन्हें स्वाभाविक मौत मरने देना है। इसे स्पष्ट करने के लिए यह बताना ज़रूरी है कि १९५६ में युवा मवेशियों की सख्या ७ लाख ६८ हजार थी जिनमें से ३ लाख १९ हजार ०-१ आयु वर्ग के थे और ४ लाख ४९ हजार १-३ आयु वर्ग के। यदि युवा मवेशियों में मृत्यु नहीं होती तो १-३ आयु वर्ग में मवेशियों की सख्या ६ लाख ३८ हजार होती। वस्तुतः अभी उनकी सख्या १९५६ से मुश्किल से ४० प्रति शत अधिक है।

इस बीच जो कमी हुई है वह मौत के कारण। इस ४० प्रति शत को मृत्यु आपात मानकर ०-१ वर्ष के आयु वर्ग में अर्ध ३ लाख १९ हजार मवेशियों की सख्या यह बताती है कि मालाना ४ लाख ५९ हजार मवेशियों का जन्म होता है और १-३ आयु वर्ग में बचे ४ लाख ४९ हजार मवेशी यह बताते हैं कि सिर्फ २ लाख २ हजार मवेशी ही जीवन के तीन वर्ष पूरे कर पाते हैं। अन्य शब्दों में ४ लाख ५९ हजार में से सिर्फ २ लाख २ हजार ही अर्थात् करीब ४४ प्रति शत ही जीवन के प्रथम तीन वर्ष पार कर वयस्कावस्था में प्रवेश पाते हैं। इस प्रकार चूँकि युवा मवेशियों की सख्या ज्यादा है और इतने अधिक वयस्क मवेशियों की ज़रूरत नहीं है अथवा

उन्हे खिलाया-पिलाया नहीं जा सकता, कुल बछड़े-बछड़ियों में से ५६ प्रति शत तक को मरने दिया जाता है। दुर्भाग्यवश यह मृत्यु अनुपात भी कुल पशुधन के विकास को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य में कि युवा नर और मादा मवेशियों का मृत्यु अनुपात करीब-करीब समान है, यह तर्क पेग किया जा सकता है कि अभी जितने बैल हैं उनमें अधिक बैलों की ज़रूरत नहीं है अथवा उनसे अधिक को खिलाया-गिलाया नहीं जा सकता। नर और मादा दोनों ही युवा मवेशियों को भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है।

इस प्रकार मवेशी विकास की समस्या केवल गुण में ह्रास होने, कम दूध देने, क्षमता की कमी, वृद्ध और अनुत्पादक पशुओं की ही नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक एक ऐसे निश्चित आकार-प्रकार के जवान पशुओं की है जो बैसे आकार-प्रकार के पशुओं की नस्ल का विकास कर उसे बनाये रखने के लिए आवश्यक आकार में भी बड़े बछड़े, बछड़ियाँ आदि पैदा कर सके। “इसी कारण उपयुक्त चुनाव और छटाई के जरिये पशुधन प्रबन्ध का तरीका ‘वैज्ञानिक ढंग से पशुधन प्रबन्ध करने के लिए’ मुख्य सिद्धान्त के तौर पर अपनाया गया है।”

अनुकूलतम सख्या

प्रत्यक्ष है कि अब वह समय आ गया है जबकि किसान को यह निर्णय लेना है कि उसे कितने बैलों की ज़रूरत खेती के लिए है और कितनी गायों की आवश्यक सख्या में बैल और दूध देने के लिए तथा कितने नर अथवा मादा मवेशियों की आवश्यक सख्या बनाये रखने के लिए। अतिरिक्त मवेशियों का निश्चय हो जाने के बाद उन्हें दूर किया जा सकता है, क्योंकि वे आर्थिक रूप में दायित्व होने के अलावा उपयोगी कर्पक पशुओं, दुधारू मवेशियों और जन-आबादी से भोजन के मामले में प्रतियोगिता करते हैं तथा उपयोगी मवेशियों की नस्ल को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न उठता है कि पालने के लिए मवेशियों की अधिकतम और अनुकूलतम सख्या क्या होनी चाहिये? सामा-

न्यतया अभी जो आठ लाख गाये हैं, वे सालाना ४ लाख ४९ हजार बछड़े-बछड़ियों को जन्म देती हैं। सिर्फ २ लाख २ हजार गायों से ही इतनी ही सख्या में बछड़े-बछड़ियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, बगैरे कि वे उन्नत नस्ल की तथा स्वस्थ हों। फिर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ४ लाख ४९ हजार बछड़े-बछड़ियों में से सिर्फ २ लाख २ हजार ही तीन वर्ष में अधिक की उम्र प्राप्त कर पाती हैं। यदि इस मजबूरन मृत्यु की सख्या आधी कर दी जाय, जोकि विशेष सावधानी बरतने पर की जा सकती है, तो ४ लाख ४९ हजार वयस्क पशुओं का स्टॉक बनाये रखने के लिए सालाना सिर्फ ३ लाख १ हजार बछड़े-बछड़ियों की पैदाइश ही जरूरी होगी। इसका अर्थ है कि ५ लाख ४१ हजार बैलों की सख्या, जोकि क्षेत्र की कुल आवश्यकता से अधिक है, बनाये रखने तथा उनकी जगह नये बैल लाने के लिए ३ लाख वयस्क गायों काफी होगी। इस प्रकार गायों की सख्या बैलों की सख्या की सिर्फ ६० प्रति शत होनी चाहिये। चूँकि बछड़े-बछड़ियों की सख्या करीब-करीब बराबर है, अतः यह आवश्यक है कि प्रति वर्ष ४० प्रति शत बछड़ियों की छटाई कर दी जाय। इससे युवा मवेशियों को अच्छा चारा मिलेगा, वयस्क मवेशी अधिक दूध देंगे और बैल अधिक काम कर सकेंगे।

मवेशी संख्या का नियंत्रण

अतिरिक्त मवेशियों की छटाई और उनकी सख्या में वृद्धि नियंत्रण इस कारण और भी आवश्यक हो जाता है कि राज्य में चरागाह भूमि की कमी हो गयी है, क्योंकि प्रत्येक इंच भूमि को खेती के लायक बमाने की कोशिश की जा रही है।

इस प्रकार प्रश्न उठता है—इनकी सख्या किस प्रकार कम और नियंत्रित की जा सकती है? चन्द विकल्प हैं—(अ) जन्म निरोध, (आ) बीमारियों और महामारियों से मृत्यु, (इ) बन्धीकरण, (ई) कत्ल, और (उ) भुखमरी। मवेशियों के मामले में जन्म निरोध सम्भव नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में कोई तरीका निकाल भी लिया गया तो गायों का १२वा हिस्सा भी दुग्ध उत्पादन कार्य के लिए नहीं रखा जा सकेगा और अनाधिक

रूप में इतनी बड़ी सख्या में उनका पालन बिना किसी लाभ के करना असम्भव हो जायेगा। बीमारियों और महामारियों से मरने देना वाछनीय नहीं है, क्योंकि इसका असर सम्पूर्ण मवेशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ेगा। बन्धीकरण के कई लाभ हैं, परन्तु इस दिशा में अब तक चिकित्सा भुविधाओं की कमी के कारण कुछ नहीं किया गया है। चौथा विकल्प अर्थात् जेकार पशुओं का कत्ल आर्थिक रूप में लाभप्रद जरूर है, परन्तु सामाजिक और धार्मिक रूप में इस पर बहुत मतभेद है, और हमारे सांस्कृतिक तथा परम्परागत मूल्यों के अनुरूप भी नहीं है। इस प्रकार एक ही विकल्प और बच जाना है, और वह है जानबूझ कर जानवरों को चारे और ठीक से देखभाल के बिना मर जाने देना। यह प्रथा जोरदार रूप में प्रचलित है, भले ही प्रकट रूप में ऐसा कुछ नजर न आता हो, और यह अविवेकपूर्ण, अनार्थिक तथा व्यर्थ है। भूख में मरे जानवरों की खालें भी निष्कृष्ट श्रेणी की होती हैं और उनमें मांस, चर्बी आदि भी अधिक प्राप्त नहीं होते।

चन्द आवश्यक उपाय

किसान यह जानता है कि बिना चुनिन्दा मवेशी रखे वह उनकी पूरी देखभाल नहीं कर सकता, परन्तु कानूनी और सामाजिक प्रतिबन्ध इस सम्बन्ध में उसकी पहल में रुकावट डालते हैं। इस दिशा में एक निर्भीक और फलमूलक कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है तथा सदियों पुरानी परम्पराओं को वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त ढंग से परिवर्तित करना है।

मवेशियों की सख्या में विवेकपूर्ण वृद्धि, बेकार पशुओं का पूर्ण बन्धीकरण और अनुत्पादक गायों का अनुवरीकरण कार्य अपनाया जाना चाहिये। बाकी गायों की दूध देने की क्षमता को भी मान्य साडों के जरिये ही प्रजनन कर सुधारना होगा। सम्भोग मध्यान्तर को अल्प बना, गायों और साडों को एक साथ रखने पर प्रतिबन्ध लगा सम्भोग में नियंत्रण कर, गायों को गामिन करने की क्षमता के आधार पर साडों को चिन्हित करना तथा उपयुक्त जननिक गुणों का विकास करना होगा।

सूखी बेकार गायो, अन्य बेकार मवेशियो और दूध देनेवाले एव उपयोगी मवेशियो के बीच उचित सतुलन प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिये। यदि यह किया जा सका तो दुग्ध उत्पादन पर डमका असर पड़ेगा, परन्तु इससे रख-रखाव खर्च में काफी कमी हो जायेगी और उसी के अनुसार दुग्ध उत्पादन खर्च में भी उतनी ही कमी हो जायेगी। काम आनेवाले पशुओं की पूर्ति पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गायों की संख्या कम होने में बाकी वचे मवेशियो को अधिक तथा पौष्टिक खुराक मिल सकेगी, गायें जल्दी गाभिन हो सकेगी, उनकी अन्तर्वर्ती अवधि कम हो जायेगी और वे दिनोदिन अधिक बछड़े तथा दूध देने लायक हो सकेगी।

लघु-कालीन दृष्टि से सरकार को अयोग्य, बेकार और अनुत्पादक मवेशियो को अपने कब्जे में ले लेना चाहिये, जोकि अभी योग्य मवेशियो को उनके भोजन और चारे से वंचित कर रहे हैं ताकि वे कृषि पर बोझ न बने रहे। इस सब के अलावा चरागाह भी बढ़ाने

त्रण के मामले में, नहीं बनाया है और न ही कोई बड़ा पशुपालन तथा दूग्ध उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रथम तीन योजनाओं में कुल १ अरब २२ करोड़ के प्रावधान में से इस विभाग के लिए सिर्फ दो करोड़ रुपये ही दिये गये।

तालिका छ दर्शाती है कि न सिर्फ कुल योजना खर्च को देखते हुए इस विभाग के लिए दी गयी निधि नगण्य रही, बल्कि प्रस्तावित निधि, विशेष कर प्रथम और द्वितीय योजनाओं की अवधि में, खर्च भी नहीं हो पायी। इसका परिणाम यह निकला कि जो छोटी-मोटी सुविधाएँ और पूर्ति आवश्यक मानी जाती थी उनकी भी उपलब्धि नहीं की गयी।

बड़ी विचित्र बात है कि जो विभाग राज्य की कुल आय में करीब १५ प्रति शत योगदान देता है उस पर मुश्किल से १ में २ प्रति शत निवेशगत पूँजी खर्च की गयी है। भौतिक रूप में भी कोई खास सुधार नहीं दिखाई

तालिका ६

सन् १९५१ और १९६१ के बीच पशुपालन पर कुल निवेश और १९६१-६५ की अवधि में अनुमानित खर्च (लाख रुपयों में)

वर्ष	पशुपालन के लिए कुल प्रावधान (१)	वास्तविक खर्च (२)	योजना का कुल खर्च (३)	३ के प्राति- शान्य स्वरूप १ (४)
१९४७ (योजना से पूर्व)	२ २६	—	—	—
१९५१-५६	२४ ३८	२२ १६	१,२७४ ०७	१ ९
१९५६-६१	७४ ५७	४६ ५५	३,३९० ००	२ २
१९६१-६५ (अनुमानित)	१०० ००	अनुपलब्ध	७,५०० ००	१ ३

की आवश्यकता है ताकि अधिक चारा मिल सके और उसे योग्य मवेशियो को खिलाया जा सके। चरागाह के विकास के लिए एक निश्चित संयोजित कार्यक्रम किसी किस्म की फसल योजना के अन्तर्गत होना चाहिये।

सरकारी निरपेक्षता

यहाँ इस सम्बन्ध में इस बात की समीक्षा करना उपयुक्त होगा कि पिछले १३ वर्षों में इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या किया है। प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में इस विभाग का प्रत्यक्ष महत्व होते हुए भी राज्य सरकार ने पशुधन विकास के लिए कोई विस्तृत और समग्र कार्यक्रम, विशेष कर अतिरिक्त मख्या के निय-

देना। प्रत्येक ६७ हजार मवेशियो के लिए एक अव्यवस्थित अस्पताल है, प्रत्येक २४ हजार मवेशियो के लिए एक छोटा-सा दवाखाना है, प्रत्येक १,३३० के लिए प्राथमिक उपचार केन्द्र है और प्रत्येक ८७ हजार के लिए एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र है। जब तक पशुधन प्रबन्ध और विकास के लिए—सख्या नियंत्रण अथवा नस्ल सुधार के अतिरिक्त—योजित कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जाना, तब तक राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत नस्ल के मवेशियो का प्राप्त करना मुश्किल ही लगता है।

बल्लभ विद्यानगर (गुजरात). १६ जुलाई १९६४

मद्रास के एक गाँव का आर्थिक चित्र

त. सो. यशवन्त और ने. सु. तिरुवेंकटाचारी

मद्रास राज्य के उत्तर आर्कोट जिले में स्थित वगाई गाँव की अर्थ-व्यवस्था के अध्ययन से पता चलता है कि काश्तकारी की सुरक्षा-विहीन अवस्थाओं और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण अधिकांश आबादी बड़ी मुश्किल से गुजर-बसर कर सकती है। साठ प्रति शत परिवार पूरक वृत्ति के रूप में हाथ करघा बुनाई पर निर्भर करते हैं, परन्तु इस उद्योग की अवस्था भी कोई विशेष अच्छी नहीं है।

वगाई गाँव मद्रास राज्य में उत्तर आर्कोट जिले के चेटयंग तालुके में है। मद्रास-वडीवाग सड़क पर ५६वे मील पर एक गाँव है दुसी, वस से वही उतर कर ठम गाँव में पहुँचा जा सकता है। वगाई का क्षेत्रफल है ४१६ ५४ एकड़ और आबादी है ४०२, जोकि ७९ परिवारों में बटी है। यहाँ में काजीवरम् गहर सिर्फ छ मील दूर है। काजीवरम् अपनी हाथ करघा रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वगाई में एक पुरवा भी है नत-कोल्लई, जोकि गाँव के मध्य भाग में तीन फलंग की दूरी है।

जातियाँ और आबादी

वगाई गाँव में वन्य जाति के लोगों की संख्या अधिक है। तालिका १ में जातिवार परिवारों के आकड़े दिये गये हैं।

तालिका १

वगाई में जातिवार परिवार

जाति	परिवार संख्या	कुल का प्रातिगत्य
वन्य	७१	८९ ८
इरुला	५	६ ३
यादव	१	१ ३
विश्व-ब्राह्मण	१	१ ३
मैस्त्री (धोवी)	१	१ ३
कुल	७९	१०० ०

वन्य जाति के लोग कृषक-सह-हाथ करघा बुनकर हैं। उनके पास अधिकांशतः दुसी गाँव के ब्राह्मणों की जमीन पट्टे पर है, वे अतिरिक्त कमाई के लिए हाथ करघा

चलाते हैं—यह उनका परम्परागत पेशा नहीं है। इरुला जाति के लोग आदिवासी हैं और कृषि-मजदूरी करते हैं। अकेला यादव परिवार खेती में लगा है। विश्व-ब्राह्मण और धोवी अपना पुरतैनी धधा क्रमशः लोहारी और मुतारी तथा कपड़ा धोने का काम करते हैं। इरुला को छोड़ बाकी सभी जातियाँ सहायक धंधे के रूप में हाथ करघा बुनाई का कार्य करती हैं। ग्रामीण लोग बुनाई कार्य सिंचाई की अनिश्चितता के कारण ही करते हैं। तालिका २ में दिये गये आकड़े गाँव की भूमि-

तालिका २

वगाई में भूमि उपयोग

श्रेणी	एकड़
विशुद्ध कृष्य भूमि	२३५ ९४
एक से अधिक बार जोती गयी भूमि	१५२ ९६
अकृष्य कार्यों में लगी भूमि	१३१ ८५
पडती भूमि	४८ ७५

स्रोत विलेज रेकार्ड्स*

उपयोग पद्धति दर्शाती है, जिसके अध्ययन से हमें यह जानकारी मिलती है कि इस गाँव के लोग अपनी आय के मुख्य स्रोत कृषि पर कितने अधिक निर्भर हैं।

* प. अयप्पन. 'रिपोर्ट ऑन दि सोशियो-इकनॉमिक कंडीशंस ऑफ दि एगोरीजनल ट्राइब्स ऑफ दि प्रोविन्स ऑफ मद्रास,' पृष्ठ १०१-१०५।

खेती के अन्तर्गत और भी ४८ ७५ एकड़ भूमि लायी जा सकती है। मंडक, निवास आदि जैसे अकृषक कार्यों में १३१ ८५ एकड़ भूमि है। सिंचित भूमि १६० २७ एकड़ है तथा असिंचित भूमि १२४ ४२ एकड़। सिंचित व असिंचित दोनों ही प्रकार की भूमि पर धान की खेती की जाती है। गांव के लिए सिंचाई का स्रोत है मैमनदुर हिस्सा तालाब, जोकि पानी के लिए पालार एबीकट नहर पर निर्भर करता है। सिंचाई के लिए ३२ गांव डम मैमनदुर हिस्सा तालाब पर निर्भर करते हैं। इस तालाब को नियमित रूप में पानी नहीं मिलता, क्योंकि पानी पूर्ति करनेवाली नाली १९३१ की बाढ़ के कारण कीचड़ से भर गयी थी। इस कारण अधिकांश वर्षों में तालाब पूरा भर नहीं पाता, जिस कारण फसल का न होना आम बात है। सरकार नाली की छंटाई का काम कर सकती है; क्योंकि वह गांव का जीवन-स्रोत है।

तालिका ३

वर्गाई की फसले

फसल	फसल के अन्तर्गत क्षेत्र (एकड़ में)	कुल का प्राति- शत्य
धान	३३९ ५४	८७ ३
मूंगफली	३८ ८१	१० ०
रागी	५ ०६	१ ३
अन्य*	५ ४९	१ ४
कुल	३८८ ९०	१०० ०

स्रोत विलेज रेकार्ड्स।

* बारागु, तरकारिया, ढाल आदि शामिल हैं।

धान सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। धान और रागी आदि तथा मूंगफली की फसले शुष्क फसलों के रूप में पैदा की जाती हैं। साल में दो फसले पैदा की जाती हैं, यद्यपि बहुत कुछ मैमनदुर हिस्सा तालाब में उपलब्ध जल पर निर्भर करता है। अगर तालाब में काफी

पानी होता है तो साल में धान की तीसरी फसल भी पैदा की जाती है।

खेती

खेती में चन्द अच्छे मुधार हुए हैं। लोहे के हल चलाये जाते हैं और उर्वरकों का भी आम इस्तेमाल होता है। कृषकों की आम गिकायत यह है कि उन्हें मैमनदुर की बहुधर्मी सहकारी समिति से उचित दर तथा उपयुक्त समय पर पर्याप्त उर्वरक नहीं मिलते, जिसका कारण यह है कि उक्त समिति को कई गांवों को उर्वरकों की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि कई छोटे किसानों को उर्वरक नहीं मिल पाते। कुछ किसानों को उर्वरक ऊँची दर पर अन्य स्रोतों से खरीदने पड़ते हैं। प्रति एकड़ ५० से २२० पौड उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है और अनाज (धान) की उत्पादन वृद्धि के लिए यह अनुकूल कारक है। प्रति एकड़ धान की उपज १२ बोरा (१,५१२ पौड) है, जोकि कई गुनी बढ़ायी जा सकती है, यदि समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक दिये जायें। गांव में ३५ काश्तकार हैं, जोकि सुरक्षा की कमी और उत्पादन में उचित हिस्सा न मिलने के कारण भुगतते हैं। अभी काश्तकार को कुल उत्पादन का करीब ४५ प्रतिशत मिलता है। खेती का सारा खर्च काश्तकार को देना होता है, जबकि भू-स्वामी भूमि-राजस्व ही चुकाना है।

सहायक उद्योग

एक ओर प्रतिकूल काश्तकारी और दूसरी ओर मैमनदुर हिस्सा तालाब से जल-पूर्ति की अनिश्चितता होने से अधिकांश आबादी, दूसरे गांव के काश्तकारों सहित, घाटे की जोखिम उठाती है। हाथ करवा बुनाई ही उन्हें बचाती है। दुर्भाग्यवश, इस धंधे में भी उन्हें कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि वे काजीवरम् शहर के निकट रहने-वाले मास्टर बुनकरों के अन्तर्गत काम करते हैं। बुनकरों को बहुत-कुछ मजदूर ही समझा जाता है और उन्हें

मजदूरी, जितना कपडा वे बुनते हैं उसके हिमाव में दी जाती है। करीब ६० प्रति शत परिवार हाथ करघा बुनाई में लगे हैं, जोकि उनका पारिवारिक उद्यम बन गया है। प्रत्येक घर में उडन ढकीं करघे इस्तेमाल किये जाते हैं। बुनकरो के पास अपने करघे हैं और अधिकांश मामलों में बुनाई कार्य अपने घरों में ही किया जाता है।

हाथ करघा उद्योग की आर्थिक स्थिति का रूप इस प्रकार है मास्टर बुनकर कारीगर बुनकर को सूत सप्लाई करता है, बुनकर उसमें साडी और कैली (रंगीन लुगी) जैसी वस्तुएँ बुन कर लौटा देता है। कुछ समय में अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया आदि विदेशों में ये वस्तुएँ लोकप्रिय होती जा रही हैं। अब रेशमी साड़ियों की बुनाई को अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि सूती साड़ियों अथवा कैलियों की बुनाई की तुलना में उनमें अधिक पैसों मिलते हैं।

हाथ करघा बुनकरो की अवस्था

एक परिवार (वयस्क पुरुष, वयस्क नारी और एक मददगार) एक चित्तम सूत से एक गज साडी बुन सकता है। मजदूरी ७५ पैसे से १ रुपया गज है। इस प्रकार एक परिवार मजदूरी स्वरूप ७० से ८० रुपये महीना कमा सकता है, यदि वह माह में १५-१६ दिन काम करे। चूँकि सूत की सप्लाई, जोकि स्वयं अधिकांशतः बाजार की माँग पर निर्भर करती है, मास्टर बुनकर अनियमित रूप से करता है अतः बुनकरो की रोजगारी अनिश्चित और अनियमित रहती है। इसके मौसमी होने का एक

कारण यह भी है कि वर्तमान के दिनों में बुनाई करना सम्भव नहीं है, क्योंकि नाना-वनाने आदि जैसे प्राथमिक कार्य जोकि खुले में किये जाते हैं, नहीं किये जा सकते। हमेशा रोजगारी न मिलने के कारण आमदनी कम होती है, जिसमें बहुत-से बुनकरो को मास्टर बुनकरो के चंगुल में मजबूरन फँसना पड़ता है, जोकि उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बड़े भाग की पूर्ति करते हैं।

उपसंहार

मास्टर बुनकरो के अन्तर्गत काम करनेवाले हाथ करघा बुनकरो की दयनीय अवस्था है। ग्रामीणों ने दुसरी की सहकारी समिति का उपयोग करते हुए अपनी सहकारी मस्था बनाने की दृष्टि जाहिर की है। परन्तु उनके लक्ष्य की पूर्ति में मुख्य बाधाएँ पूँजी और सहकारी समिति के सदस्यों में धन की कमी है। आशा है कि नयी पचायत अपने प्रबुद्ध नेतृत्व में गाँव के गुटबन्द समाज को सुधारने का जो प्रयास कर रही है, उससे ग्रामीणों की आर्थिक अवस्था सुधरेगी। कई कमियों और कमजोरियों के बाद भी अन्ततः यह कहा जा सकता है कि गाँव में हाथ करघा उद्योग कृषि का सुखद अवलम्ब है।

अध्ययन में वगाई की अर्थ-व्यवस्था का उज्ज्वल चित्र नहीं मिलता। कृषि और उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि न होने के कारण है—मिच्राई की कमी, वित्त की कमी, उर्वरकों की कमी, मास्टर बुनकरो के अन्तर्गत काम करना, आदि। अतः ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को पुनः प्राणवान बनाने के लिए कार्यवाही करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

मद्रास २ जुलाई १९६४



दक्षिण कन्नरा में बदलौन व्यापार

नवीनचन्द्र कृ. तिगलाया

प्रस्तुत लेख में मैसूर राज्य के दक्षिण कन्नरा जिले के किसानों और मछियारियों के बीच प्रचलित बदलौन व्यापार की जनोखी विशिष्टताओं का विश्लेषण किया गया है।

भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ कि विक्री योग्य कुल अतिरिक्त कृषि सामग्री का करीब ६० प्रति शत ग्राम स्तर पर ही बिक जाता है, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बदलौन व्यापार अभी भी प्रचलित है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इन क्षेत्रों में मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को जिस के रूप में पारिश्रमिक चुकाना आम बात है। रिपोर्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ राइस इन इण्डिया के अनुसार कुल धान उत्पादन का करीब १७ प्रति शत किसानों द्वारा बदलौन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।^१ यद्यपि यह प्रातिशत्य बिल्कुल नगण्य है, बड़ी संख्या में अल्पक ग्रामीणों के आर्थिक कल्याण में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बदलौन व्यापार कृषि उत्पादकों तथा ग्रामीण फेरीवालों, कारीगरों और अन्य छोटे-छोट व्यापारियों के बीच विनिमय की प्रचलित विधि है। इस लेख में मैसूर राज्य के दक्षिण कन्नरा जिले में किसानों और मछेरियों के बीच चलने-वाले बदलौन व्यापार की विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

सामान्य पृष्ठभूमि

जिले की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ हे विकसित हो रही कृषि, भरपूर जंगली खेत और विविध मत्स्य उद्योग। जिले की मुख्य फसल है धान और कुल राष्ट्रीय धान उत्पादन में प्रत्येक जिले के प्रातिशत्य योग-

दान के अनुसार देश के १७१ धान पैदा करनेवाले जिलों में इसका स्थान ३८वाँ है।^२ यद्यपि यहाँ धान की खेती बारिश पर निर्भर है, उत्पादन दर देश की चन्द सर्वोच्च उत्पादन दरों के बराबर है। मत्स्य धन के मामले में भी यह जिला बड़े स्तरों में से एक है। यहाँ के मछुओं का जीवन भौतिक साधनों अथवा जीवन-स्तर के बदले आनन्ददायक रीति-रिवाजों और सामाजिक संगठनों से परिपूर्ण होता जाता है।^३ मछली पकड़ने के मौसम में जो अतिरिक्त मछलियाँ बच जाती हैं, उन्हें पुराने तरीके से नमक लगा कर और सुखा कर आरक्षित रखते हैं। बहुत-से बियवानिये नमक लगी मछलियों का व्यापार करते हैं और तमिलनाडु तथा श्रीलंका में महज ही इनकी बिक्री हो जाती है।

यहाँ दिये जा रहे आकड़े बदलौन-व्यापारवाली सामग्रियों की मात्रा के मुख्य सूचकांक हैं। जिले में उत्पादित कुल २,३८,६५० टन चावल (१९६०-६१) में से करीब ३,०४० टन (कुल उत्पादन का १७ प्रति शत) का विनिमय बदलौन व्यापार के जरिये होता है। सूखी मछलियों के सम्बन्ध में आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, रिपोर्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ फिश इन इण्डिया के अनुसार २,३८,४५० मन मछलियों पर दक्षिण कन्नरा के सरकारी याडों में नमक लगाया जाता है।^४ चकि याडों के बाहर भी उतनी ही मछलियों पर

१ रिपोर्ट ऑन दि मार्केटिंग ऑफ राइस इन इंडिया, भारत सरकार, द्वितीय संस्करण, १९५५।

२ एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, अगस्त १९५९, पृष्ठ ६१६।

३ विस्तृत विवरण के लिए देखें 'दक्षिण कन्नरा के मछुवाही गाँवों का सामाजिक संगठन', खादी ग्रामीणोद्योग, जुलाई १९६२।

४ रिपोर्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ फिश इन इंडिया, द्वितीय संस्करण, १९६१, पृष्ठ ७९।

नमक लगाया जाता है, अतः नमक लगायी जानेवाली मछलियों की मात्रा ५,००,००० मन मानी जा सकती है। इसमें से करीब १,००० मन का बदलौन व्यापार में टस्तेमाल होता है और बाकी बिक्री माध्यमों के जरिये जिले के मछली खानेवाले लोगों अथवा मद्रास राज्य और श्रीलंका के व्यापारियों को बेच दी जाती है।

बदलौन व्यापार

किसानों और मछलों के बीच धान और मछली के विनिमय में व्यापार को मुवाई पोपिनी कहते हैं, जिसका अर्थ है “पूर्वी गाँवों में जा रहे हैं” अर्थात् पश्चिम के तटीय मछलीमार गाँवों से मछलियाँ अपने माल के साथ अन्दर के गाँवों में जाती हैं। इस प्रकार बदलौन व्यापार मछलीमार केन्द्रों से २०-२५ मील की त्रिज्या के अन्तर्गत उन गाँवों में होता है जहाँ कि जल्दी पहुँचना कठिन है। मछलियाँ मगूह में सर पर मछली की टोकरी रखे और कभी-कभी दिन-रात कहीं-कहीं ठहरती हुई अपनी मछली के बदले धान अथवा चावल प्राप्त करने के लिए मार्ग रास्ता तय करती हैं। सम्भवतः खेतों के आस-पास सूखी मछली की पूर्ति करने की वजह से ही उनकी माग बनी रहती है।

विनिमय की दर

धान और सूखी मछली के बीच बदलौन शर्तें अथवा विनिमय की दर प्रभावित करनेवाला मुख्य कारक सम्बन्धित वर्गों द्वारा दोनों किस्म के माल की माँग का परिमाण है। चावल सम्बन्धी मछलियों की माँग अपेक्षितया वर्षों तक एक ही बनी रहती है। चूँकि मछलियाँ बदले में अपने परिवार की वार्षिक आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त चावल प्राप्त कर लेना चाहती हैं, अतः वे बदले में कम चावल मिलने पर भी उसे लेने को तैयार रहती हैं, जबकि किसान परिवारों में मछली की माँग उनकी रमोई-वाटिकाओं में पैदा हुई तरकारियों से व्युत्क्रमानुपातिक रूप से सम्बन्धित है। प्रस्थापित सीमान्त दर की हिकसियन शब्दावली में विनिमय प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए यह

कहा जा सकता है कि सूखी मछली प्राप्त करने की इच्छा चावल की माँग की पूर्ति से जल्दी हो सकती है। अतः कुछ समय के बाद व्यापार की शर्तें, मछलियों के लिए अनुकूल नहीं भी हो सकती हैं और चावल प्राप्त करने के लिए अभी से कहीं अधिक मछली देनी पड़ सकती है। इसके विपरीत किसान परिवार मछली लेकर अपेक्षितया अच्छी दर पर चावल देने के बदले उसे जमा रखना पसन्द कर सकते हैं। अतः मछलियाँ अगर और बदलौन करना चाहेंगी तो तरकारियाँ देंगे, क्योंकि अब तक वे काफी सूखी मछली खा चुके हैं और बदले में चावल देना उपयुक्त नहीं समझते। उन्हें वे मछली से उत्तम मानते हैं।

उत्तरी भागों में प्रचलित

इन दो प्रकार के प्राथमिक उत्पादनों के बीच-चावल और सूखी मछली का-बदलौन व्यापार जिले में ५० वर्षों में भी अधिक से प्रचलित है। जिले के सम्बन्ध में जो सबसे पुराना अधिकृत प्रतिवेदन प्राप्त है, उसमें भी उसकी परीक्षा सूचना है। जिले के दक्षिणी भागों के निम्नलिखित उत्तरी भागों (होस्बेट से मालपे तक) में यह व्यापक रूप से प्रचलित था। इसका कारण दोनों भागों में सड़क और परिवहन सुविधाओं के फर्क से जाना जा सकता है। चूँकि दक्षिणी भागों में अच्छी सड़कें और नियमित परिवहन सुविधाएँ हैं, अतः दूरस्थ गाँवों में भी लोग किसी न किसी वाज़ार तक सहज ही पहुँच सकते हैं। अतः इस भाग में इन वस्तुओं में बदलौन व्यापार नहीं होता। उत्तरी भाग में सड़कों की कमी और अधिकांश गाँवों तक सहज ही न पहुँच सकने के कारण किसान परिवारों को मछली प्राप्त करने के लिए मछलियों और उनके बदलौन व्यापार पर निर्भर करना पड़ता है। इस प्रकार अन्य विचवानियों के न होने पर मछलियाँ नमक लगाने, सुखाने और दूर-दूर बसे अपने ग्राहकों को मछली देने का काम करती आ रही हैं।

बदलौन व्यापार उनके दैनिक जीवन का अंग बन गया है। मछलियों की ग्राम सभा की इसे स्वीकृति प्राप्त

है। मछेरिना और किसान परिवारों के बीच रीति-रिवाजों और आपसी सहमति से सम्पर्क स्थापित हो जाता है। विभिन्न गाँवों में मछेरिनों के अपने बंधे ग्राहक हैं जिनके यहाँ कोई दूसरी मछेरिन मछली बेच ही नहीं सकती, अतः उनके यहाँ दूसरा कोई जाता ही नहीं। यह परम्परागत अनुबध्द मछुओं द्वारा इतनी ईमानदारी से निभाया जाता है कि ग्राहकों पर उनका अधिकार-सा हो जाता है, और लोग इसे मानते भी हैं। ग्राम सभा का इन रीतियों तथा अन्य कई सामाजिक गतिविधियों पर इतना जबरदस्त अधिकार रहा है कि पचास वर्षों से बदलौन व्यापार पद्धति उनके परम्परागत जीवन का अंग बनी रही है।

ग्राम सभा का अधिकार

पिछले पचास वर्षों से यह परम्परागत बदलौन व्यापार इसलिए जिंदा रह सका है कि मछेरिनों को इससे आर्थिक लाभ होता है। चूँकि उसे बदलौन व्यापार से साल भर के लिए चावल मिल जाता है, वह अनाज बाजार की घट-बढ़ से मुक्त हो जाती है। वरसात के दिनों में जब मछली पकड़ने का काम बन्द हो जाता है तो मछेरिन परिवार के पास जीविका अर्जित करने के लिए कोई काम नहीं होता और उसके पास मौसम में सूखी मछलियाँ देकर जमा किया गया चावल ही बचा रह जाता है। युद्धकाल के पूर्व के वर्षों में उसे बदलौन व्यापार के जरिये अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त चावल मिल जाता था, और वह आषाढ के दिनों में भूखो मरने से बच जाती थी। ऐसा शायद ही कभी होता था कि मछुआ परिवारों के पास साल भर खाने के लिए पूरा चावल हो, जबकि किसान परिवारों के पास उसकी कमी हो।

तथापि, हाल के वर्षों में बदलौन व्यापार में ह्रास होता जा रहा है। यह कई आर्थिक कारणों से है जोकि धीरे-धीरे ग्राम्य जीवन के क्रम और पद्धति को परिवर्तित कर रहे हैं। प्रथम, धातु-टंकन प्रक्रिया अर्थात् रुपये-पैसे के प्रचलन ने धीमी गति के बावजूद बदलौन व्यापार के आकर्षण को कम कर दिया है। युद्ध के समय से अनाज

के भाव में बढोतरी होते रहने से किमान अधिकाधिक बाजार मुखी होते जा रहे हैं, विशेष कर उत्तम अनाज बेचने के मामले में। वे अपना सारा उत्पादन (घर खर्च के लिए थोड़ा-सा रख कर) गाँव के वनिये को बेच देते हैं। अब उन्हें सूखी मछलियों परम्परागत मछेरिनों से नहीं खरीदनी पड़ती, उनकी जगह छोटे-छोटे मछली व्यापारियों ने ले ली है और वे नकद व्यापार करते हैं।

मडक और परिवहन पद्धति के विकास ने दक्षिण कॅनरा के गाँवों में बदलौन व्यापार कार्य को अधिकाधिक मन्दा कर दिया है। दूरस्थ गाँवों में साइकिल से सहज ही पहुँच सकने के कारण अब मछेरिनों का गाँव-गाँव घूम कर बेचने का काम बन्द हो गया है। छोटे-छोटे मछली व्यापारी साइकिल पर मछली लाद कर कई बार गाँवों में घूम जाते हैं।

बदलौन व्यापार में ह्रास

फिर, इधर हाल में मछुआ समाज में शिक्षा के प्रसार से, इस पुरानी पद्धति को बेकार माना जा रहा है। इसके बदले वे अपना माल बिक्री के लिए निकटस्थ शहरों में ले जाते हैं। वे उन व्यापारियों के हाथ भी अपना माल बेच देते हैं जो अपनी गाड़ी उनके दरवाजे पर लाकर उनसे नकद देकर खरीद लेते हैं। और, किसानों द्वारा मजबूरन माल बेचने की जो बात कही जाती है, वह भी इस मामले में बिल्कुल सही है, जैसे कहा जाता है “किमानों की अवस्था जिनके पास पैसा है, बाजार है और परिवहन है, उसके साथ प्रायः यदि वह कर सकता है तो, सोदेवाजी करने की होती है।”^६

इस प्रकार सूखी मछली और चावल का बदलौन व्यापार अब समाप्त होने की अवस्था में आ गया है। एक समय था जबकि यह मछुओं के जीवन और थम का अविभाज्य अंग था। आज यह करीब-करीब भूत-कालीन वस्तु बन गया है।

बम्बई २२ जून १९६४

^६ रूरल क्रेडिट सर्वे जनरल रिपोर्ट, मश्रित सम्पादन, पृष्ठ ३७।

भ्रष्टाचार निवारण के लिए उपाय

भारत सरकार ने संसद सदस्य श्री के. मन्तानम की अध्यक्षता में 'भ्रष्टाचार निवारण समिति' का गठन किया। अन्य बातों के साथ-साथ समिति से "इस प्रकार के नए तुले उपाय सुझाने के लिए कहा गया कि उनके फल-स्वरूप जन-सेवकों एवं सामान्य जनता दोनों में ही एक ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित हो, जिसमें घसखोरी और भ्रष्टाचार न पनप सके। अध्यक्ष के अतिरिक्त समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार थे - संसद सदस्य श्री मन्तोष कुमार वसु, श्री टी. का. राम पाली-वाल, श्री आर. के. खाडीलकर, श्री नाथ पें और श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी, प्रशासनात्मक सतर्कता सम्भाग के निदेशक श्री एल. पी. सिंह और स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के इन्स्पेक्टर जनरल श्री डी. पी. कोहली। प्रशासनात्मक सतर्कता सम्भाग के संयुक्त निदेशक श्री टी. सी. ए. रामानुजाचारी समिति के सचिव थे।

भ्रष्टाचार निवारण के लिए समिति ने जो सुझाव दिये हैं उनमें से कुछ संज्ञाव (प्रतिवेदन का छठवाँ अध्याय) यहां पुनः प्रकाशित किये जा रहे हैं।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन अथवा यहाँ तक कि किसी उल्लेखनीय सीमा तक उसमें कभी भी तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि तत्सम्बन्धी निरोधक उपायोको योजन-बद्ध रूप में एक अविरल और प्रभाव-शाली ढंग से कार्यान्वित न किया जाय। निरोधक कार्रवाई में, आवश्यक रूप से ही प्रशासनात्मक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उपाय शामिल होने चाहिये।

भ्रष्टाचार रोकने और उसके लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए, जो सत्यनिष्ठा के मार्ग से विमुख करनेवाले किसी भी लालच को बड़े जोरदार रूप में निरुत्साहित करेगा, मुख्य प्रयास स्वयं मंत्रालय-विभाग की तरफ से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में जिम्मेवारी को मानना, उस पर ज़ोर देना और उसे स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी समझ लेना है कि कुछ मामले सामने आने पर कार्रवाई मात्र करने से ही काम नहीं चलेगा वरन् मवेदनशील स्थलों पर अनवरत निगरानी रखना और उन्हें खोज निकालना कितना ही अधिक महत्वपूर्ण है। (अ) विवेकाधीन शक्तियों, (आ) उक्त शक्तियों को अमल में लाने के स्तरो, (इ) इन शक्तियों को काम में लाने के ढंग, (ई) इस प्रकार की शक्तियों के प्रयोग

पर पदसोपान (हीरार्की) के भीतर काम में लाये जाने वाले नियंत्रण, और (उ) जिन स्थितियों में तथा जिन कामों के लिए नागरिक मंत्रालय और/या विभाग के सम्पर्क में आते हैं, उनकी सूची बनाने के लिए कानूनी, नियमों, तौर-तरीकों तथा कार्य-पद्धतियों की सुव्यवस्थित व परिपूर्ण समीक्षा की जानी चाहिये।

परिपूर्ण अध्ययन आवश्यक

इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्रालय / विभाग / प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की सीमा, गुणाङ्क और रूप के, यदि कोई निरोधात्मक और शोधक उपाय निर्धारित हो तो, उनका और उनकी प्रभावशालिता का गहन अध्ययन किया जाना चाहिये। यह देख कर हमें खेद होता है कि अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक मंत्रालय / विभाग / प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में इस प्रकार के अध्ययन प्राथमिकता के आधार पर शुरू किये जायें, और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सेण्ट्रल विजीलेन्स कमीशन) को भी चाहिये कि वह इस महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दे। इसके लिए आयोग को सरकार आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान कर सकती है।

कलकत्ता और बम्बई में हम लोग जिन व्यावसायिक और व्यापारिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिले, उन्होंने प्रायः एक स्वर में बताया कि लायसेंस देने और दुर्लभ सामग्री के बटन जैसे मामले में व्यापारिक सगठनों अथवा उनके प्रतिनिधियों को शामिल न किये जाने से किसी हद तक अनाचार और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रार्थी की योग्यता के सम्बन्ध में सरकार को क्षेत्र में काम करनेवाले अपने अधिकारियों के प्रतिवेदनो पर निर्भर करना पड़ता है। ये अधिकारी मदैव ही वास्तविक स्थिति का सही-सही मूल्यांकन कर सकने की स्थिति में नहीं होते। तथापि, प्रत्येक योग्य व्यापारिक सगठन यह जानता है कि व्यापार में कौन अमली है, और कौन से व्यक्ति चरित्रवान हैं तथा कौन से नहीं। हम से यह भी कहा गया कि यदि व्यापारिक सगठनों को सामने आने का मौका दिया जाता है तो वे अपनी जानकारी सरकार को अवश्य उपलब्ध करायेगे। कुछ जिम्मेवार व्यापारिक सगठनों ने लायसेंस देने और दुर्लभ सामग्री के बटन की पूर्ण जिम्मेवारी लेने से जो इन्कार किया वह हमारी दृष्टि से ठीक ही है। वे केवल परमाशंकाता के रूप में ही अपनी भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। हम इसे एक बहुत ही सहायक दृष्टिकोण समझते हैं और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

व्यापारिक संगठन

हम यह स्वीकार करते हैं कि जब तक व्यापारिक सगठन वास्तव में प्रतिनिध्यात्मक नहीं होते, तब तक अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आयेगी। ये सगठन स्वैच्छिक हैं और निष्कासन के सिवाय उनमें कोई दण्डिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि सगठन से निष्कासन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि वैसा करने का परिणाम यह नहीं निकलता कि निष्कासित सदस्य लायसेंस अथवा परमिट प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा। इस प्रकार किसी व्यापारिक सगठन का मदस्य बनने के लिए कोई उत्प्रेरणा नहीं है और ऐसे मामले देखने में आये हैं कि सम्बद्ध

व्यापारिक सगठन से बाहर रह कर भी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान विभिन्न स्तरों पर—उच्चतम स्तर सहित—सरकार से सीधा सम्पर्क स्थापित करके वांछित वस्तु प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुए हैं। ऐसे मामलों से व्यापक पैमाने पर इस भावना को प्रश्रय मिलता है कि उपयुक्त सम्पर्क स्थापित करके कुछ भी किया जा कराया जा सकता है।

इस तरह की भावनाओं से कोई कम नुकसान नहीं होता है। इसलिए, हम सिफारिश करते हैं कि इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये कि किस प्रकार लायसेंस देने और दुर्लभ सामग्री के बटन कार्य में व्यापारिक सगठनों अथवा उनके प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। हमारी समझ में लायसेंस या परमिट की प्राप्ति की योग्यता के लिए किसी मान्य व्यापारिक सगठन की सदस्यता एक आवश्यक शर्त होनी चाहिये। सगठन को चाहिये कि वह आवेदकों की योग्यता, उनके पहले के काम और चरित्र के सम्बन्ध में छानबीन करके लायसेंस देनेवाले अधिकारी को सिफारिश करे। लायसेंस के अन्तर्गत प्राप्त माल के दुरुपयोग और दुरुप्रयोग की हरका तथा अनुचित लाभ प्राप्ति के लिए निर्धारित नियमों, कार्य-प्रणालियों और रूप-पत्रों में चालाकी करने के तरीकों की छानबीन करने के काम में इन सगठनों को लाभदायक रूप से शामिल किया जा सकता है। हम यह भी मानते हैं कि मान्यता प्रदान करने के सिद्धान्त, छोटे व्यापारी को संरक्षण, स्वेच्छाचारिता आदि रोकने के सम्बन्ध में अनेक विस्तृत बातें तैयार करनी पड़ेगी। हमारा मुझाव है कि व्यापारिक सगठनों के सलाह-मशविरे से सम्बद्ध मंत्रालय इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं।

व्यापार सगठनों के जिन प्रतिनिधियों और अन्य गैर अधिकारियों से हम मिले, उन्होंने जोर देकर यह बात कही कि अन्य बातों के अलावा भ्रष्टाचार के मुख्य कारण इस प्रकार हैं

१ प्रशासनात्मक विलम्ब,

२ सरकार द्वारा नियामक कार्यों के जरिये जितना प्रबन्ध वह कर सकती है, उससे अधिक काम हाथ में लेना,

३ विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विवेक की गुजाइश,

४ नागरिकों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण विभिन्न मामलों निबटाने में प्रयुक्त कष्टप्रद कार्य-प्रणालियाँ।

हम से जो कुछ कहा गया उसमें काफी मार है। हम प्रत्येक पर एक-एक करके नीचे विचार करते हैं

१. प्रशासनात्मक विलम्ब

हमारे सामने जिन व्यक्तियों ने साक्षी दी उन सभी की एक राय यही थी कि काम करने में प्रशासनात्मक विलम्ब भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। हम इस मत से सहमत हैं। हमें इसमें सन्देह नहीं कि बहुधा जानबूझ कर देर की जाती है, ताकि कुछ अवैध प्राप्ति की जा सके। प्रशासनात्मक विलम्ब को यथा सम्भव न्यूनतम करना ही चाहिये और विलम्ब के उन समस्त कारणों को दूर करने के लिए ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये, जिनमें भ्रष्टाचार की गुजाइश हो। हम समझते हैं कि प्रस्तावित 'प्रशासनात्मक सुधार विभाग' इस समस्या पर विस्तृत रूप से विचार करेगा, उसे निपटायेगा। हमारी सिफारिश है कि इस समस्या के समाधानार्थ निम्न कदम उठाये जा सकते हैं

विलम्ब से बचने के लिए उपाय

अ विलम्ब के कारण तथा उसके स्थल मालूम करने और उसकी सम्भाव्यता को कम से कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/प्रतिष्ठान को चाहिये कि वह तत्काल सभी मौजूदा कार्य-प्रणालियों और कार्य-पद्धतियों की समीक्षा करे।

आ रसीद, फाइल आदि का काम निबटाने के लिए यदि समय-सीमाएँ न बांधी गयी हो तो निर्धारित की जानी चाहिये और उनका कड़ाई से पालन होना

चाहिये। यदि किसी मामले में अनावश्यक देर हुई हो तो उसका पता लगाना और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति में जवाब तलब करना ऊपरवाले अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये।

इ अवर सचिव में नीचे के स्तरों पर सभी प्रकार की टिप्पणियों (नोटिंग) से बचा जाना चाहिये। अनु-भाग की जिम्मेदारी केवल इतनी ही होनी चाहिये कि वह पूर्व-कागजात तथा पूर्व-निर्णय पेश करे। उन मन्त्रालयों/विभागों में इस कार्य-प्रणाली का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये, जिन्हें विभिन्न प्रकार के लायसेम अथवा परिमिट देने का काम करना पड़ता है।

ई जिन स्तरों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सके उनका निर्धारण होना चाहिये और यथा सम्भव अधिक-धिक को शामिल करने के किसी भी प्रयास को निरुत्साहित किया जाय तथा यदि कहीं बैसा होता हो तो, उसके साथ कड़ाई से निबटा जाय।

२ सरकार द्वारा नियामक कार्यों के जरिये जितना प्रबन्ध वह कर सकती है, उससे अधिक काम हाथ में लेना

हम इस बात का अन्दाज लगाने की स्थिति में नहीं हैं कि यह आलोचना कितनी सही है। लेकिन यह मानना ही पड़ेगा कि उन सभी क्षेत्रों में, जहाँ सरकार नियमन और नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप करती है, भ्रष्टाचार की गुजाइश है। यह स्वीकार करना सम्भव नहीं है कि सरकार को सभी नियामक कर्तव्यों और नियंत्रण शक्तियों का परित्याग कर देना चाहिये, किन्तु प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए यह बाछनीय प्रतीत होता है कि वह अपने उत्तरदायित्व के नियामक कर्तव्यों की समीक्षा करे और वह यह भी परीक्षण करे कि क्या वे सभी आवश्यक हैं और इन कर्तव्यों की पूर्ति तथा नियंत्रण शक्तियों का उपयोग करने के ढंग में क्या कोई सुधार हो सकता है। हमारी सिफारिश है कि इस प्रकार की समीक्षा अवश्य ही की जानी चाहिये।

३. विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विवेक की गुंजाइश

विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं। उन सभी में उत्सर्ग की उच्च भावना तथा सत्यनिष्ठा समानरूप से विद्यमान नहीं होती। विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग में उत्पीड़न, दुराचार और भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश है। जहाँ हम यह मानते हैं कि शक्तियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विवेक के उपयोग को समाप्त करना सम्भव नहीं है, वहाँ यह भी है कि प्रशासन का कोई ऐसा तरीका खोज निकालना सम्भव होना चाहिये कि जिससे पूर्णता को कुछ ठेस पहुँचे तो भी दक्षता और शीघ्रतापूर्वक सार्वजनिक काम करने में एक रूप से व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कम से कम किया जा सके। इस पर भी पर्याप्त क्षेत्र ऐसा बच रहेगा जिसमें व्यक्तिगत विवेक के प्रयोग को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्तिगत विवेक के प्रयोग पर नियन्त्रण रखने के लिए उपयुक्त तरीके खोज निकालना आवश्यक होगा। अधिक उन्नत देशों में इस प्रकार के नियन्त्रण के अनेक तरीके खोज निकाले जा चुके हैं। हमारी सिफारिश है कि इसका अध्ययन किया जाय और स्थिति की आवश्यकता, देश की विशालता के कारण सामने आने-वाली कठिनाइयों तथा हमारे सविधान व न्यायशास्त्र में निहित मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए नियन्त्रण की कोई व्यवस्था बनायी जानी चाहिये।

४. नागरिकों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण विभिन्न मामले निबटाने में प्रयुक्त कष्टप्रद कार्य-प्रणालियाँ।

भारत के नागरिकों को अपने दैनिक जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में प्रशासन की सहायता लेनी पड़ती है। अनेक कारणों से प्रचलित कार्य-प्रणालियाँ ऐसी हैं कि नागरिकों के लिए शीघ्रतापूर्वक अपना काम करवा लेना वस्तुतः कठिन बना देती है। इसके अलावा,

अधिकांश नागरिक यह भी नहीं जानते अथवा यह भी कहने में समर्थ नहीं होते कि माफ-साफ और सही-सही माने में उन्हें क्या चाहिये। अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता की कमी तथा सरकारी कार्य-प्रणालियों किसी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है। इसलिए 'दलालों' तथा 'बिचवानियों' का सहारा लेना, उनके लिए आवश्यक बन जाता है। हमारी सिफारिश है कि नागरिकों को इन मामलों में शिक्षित करने के लिए गम्भीर प्रयास किये जायें तथा उपयुक्त व्यवस्था भी की जाय जिसमें दलालों व बिचवानियों की कोई ज़रूरत न रह जाय और प्रशासन के पास आसानी से पहुँचा जा सके।

इन मामलों की विस्तृत बातों में जाना हमारे लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके माने हैं विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कार्य-प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करना। इसके अलावा इस प्रकार के अध्ययन का काम हाथ में लेना हमारे अधिकार-क्षेत्र के बाहर की बात भी होती। इसलिए ये प्रश्न हम सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के लिए छोड़ देते हैं। हमें आशा है कि वे इन मामलों को उच्च प्राथमिकता देंगे।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन

यह देखने में आया है कि वस्तुओं के श्रेणीकरण, खानों के निरीक्षण, श्रम-विधियों और पच-फैसलों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, विभिन्न प्रकार के लायसेंस देने, सीमा-शुल्क स्थल पर माल के परीक्षण आदि जैसे कामों में न्यून वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों को निरीक्षण, पर्यवेक्षण, लायसेंस देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जहाँ सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सामान्य वृद्धि करना एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और जनता की कर देने की क्षमता को मद्देनजर रखते हुए किया जाना है, वहाँ देश के हित में इस बात का परीक्षण करना हितकर हो सकता है कि क्या वैसे अधिकारियों की श्रेणियों के दर्जे और वेतन की तरफ विशेष ध्यान नहीं देना चाहिये, जिन्हें कराधान

मृत्युवान परमिट और लायसेंस देने सम्बन्धी मामलों में पर्याप्त विवेक से काम लेना पड़ता है अथवा जो ऐसे काम करने हों, जिनमें उच्च सत्यनिष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सीमा-शुल्क विभाग में कूतकारों और परीक्षकों, उत्पादन और आय-कर विभागों में निरीक्षकों, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभागों, रेलवे और डाक-तार विभागों में पर्यवेक्षण का काम करने-वालों तथा अन्य ऐसी ही श्रेणियों के कर्मचारियों को यह महसूस करवाना चाहिये कि उनकी अवस्था में सुधार करने के लिए सरकार विशेष रूप से चिन्तित है। हम यह भी महसूस करते हैं कि अधिकारियों की संख्या में अनावश्यक मितव्ययिता बरतना वाञ्छनीय नहीं है। हमें अनेक गवाहों ने बताया कि जहाँ सीबे भर्ती किये गये और सहायकसेवाओं से तरक्की प्राप्त-दोगो प्रकार के-कर्मचारी हैं, वहाँ सीबे भर्ती किये गये व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा का स्तर सापेक्षिक दृष्टि में ऊँचा है। जहाँ हम किसी ऐसे क्रान्तिकारी सामान्यीकरण का समर्थन करने में असमर्थ हैं, वहाँ हम यह भी महसूस करते हैं कि इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और यदि सामान्य छाप यानी धारणा के पीछे कोई सच्चाई है तो इस दृष्टिकोण से उनके सापेक्षिक अनुपात पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो सकता है।

आवास व्यवस्था

वेतन स्तर में सुधार करने से भी अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को आवास-व्यवस्था, दवा-दारू की सुविधा प्रदान की जाय, और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, खास कर उन्हें जिन्हे अपने राज्यों से बहुत दूर काम करना पड़ता है, सहायता प्रदान की जाय। रेलवे विभाग ऐसे उपयुक्त शिक्षा केन्द्रों में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रावास स्थापित कर रहा है, जहाँ कर्मचारी-गण अपने बच्चों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामान्यतः बहल कर सकने लायक खर्च कर सकते हैं। यह वाञ्छनीय है कि अन्य विभाग भी इसका अनुगमन करें।

हमारे विचार में आवास-व्यवस्था, ओर वह भी जहाँ-कहीं सम्भव हो बस्तियों में, करने से सत्यनिष्ठा के विकास में अमूल्य सहायता मिलेगी। यदि बम्बई, कलकत्ता व मद्रास जैसे बड़े-बड़े शहरों में आय-कर, सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-कर विभागों के अधिकारियों को अपने रहने के लिए खुद मकान प्राप्त करने पर बाध्य होना पड़ता है, तो वे मकान-मालिकों ओर उनके अभिकर्ताओं के एहसानमन्द हो जाते हैं। हमारा सरकार से गम्भीरता-पूर्वक यह मुन्नाव है कि वह उपयुक्त पैमाने पर आवास-व्यवस्था करे, और जब तक वह ऐसी व्यवस्था न कर ले तब तक के लिए अपने सभी कर्मचारियों को मकान प्रदान करने के लिए आवश्यक संख्या में मकानों का अधिग्रहण करे। जब एक ही विभाग अथवा सश्रित विभागों के सरकार, कर्मचारी किसी एक बस्ती में रहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कर्मचारी समाज-विरोधी काम करे और उसका किसी को पता भी न चले या उसके सम्बन्ध में कोई बात भी न हो। प्रायः प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष ने, जिसने हमसे बातचीत की, उपयुक्त आवास-व्यवस्था की आवश्यकता प्रकट की और उसके हितकर प्रभावों का महत्व सामने रखा।

देश के आर्थिक मामलों से जिन मन्त्रालयों/विभागों का सम्बन्ध रहता है उनमें और उनमें, जिन्हें निर्माण कार्यों तथा खरीद पर बड़ी-बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, सत्यनिष्ठा त्याग देने का लालच अधिक होता है एवम् यही आकर सम्पर्क साधनेवाले अवाञ्छित व्यक्ति ओर दलाल पनपते हैं। हम सोचते हैं कि इन मन्त्रालयों में विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने और उन व्यक्तियों से अन्य सुविधाएँ स्वीकार करने के सम्बन्ध में अनौपचारिक आचार-संहिता बनाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये, जिनका उन कर्मचारियों के साथ कोई आधिकारिक व्यवहार है अथवा होनेवाला है और इन नियमों के अनुसार स्वेच्छापूर्वक चलने को प्रोत्साहन देने हेतु किसी कार्य-प्रणाली का विकास किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में प्रवर अधिकारियों को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये।

प्रवर पद पर आसीन जिस अधिकारी के अन्तर्गत कई राजपत्रित अधिकारी प्रत्यक्षन काम करते हैं उसे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के लिए कदम उठाने चाहिये कि क्या किसी अधिकारी की ईमानदारी पर शक या सुवहा करने का कोई कारण है। इससे प्रवर अधिकारी अपने अवर अधिकारियों के निकट सम्पर्क में आयेगे और इसमें यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि वे गुण का मार्ग छोड़ कर पथभ्रष्ट नहीं होते हैं।

निवारक उपाय

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निवारक उपाय हैं

१. उच्च प्रशासनात्मक पदों पर नियुक्ति करने के लिए अधिकारियों का चयन करने में भारी सावधानी बरतनी चाहिये। इन पदों पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाय जिनकी ईमानदारी शक के परे हो।

२. पहली बार अराजपत्रित से राजपत्रित (गजेटेड) पदों के लिए चयन करते वक्त जिन व्यक्तियों की ईमानदारी पर शक हो, उन्हें चयन में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

३. तरक्की देने के लिए किसी कर्मचारी का नाम पेश करना जिस अधिकारी का कर्तव्य हो उसके लिए यह आवश्यक होना चाहिये कि वह इस बाबत एक प्रमाणपत्र दे कि “उसने सरकारी कर्मचारी की सेवा कारिकॉर्ड देखा है और वह इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट है कि उक्त सरकारी कर्मचारी ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति है।”

४. जन सेवा की अपरिहार्यताओं के अनुसार उन व्यक्तियों की सेवा की अवधि बढ़ाने अथवा उन्हें पुन नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ती है जो कार्य-मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं तथा सेवा-निवृत्त होनेवाले हैं अथवा हो गये हैं। इस प्रकार के कर्मचारी सार्वजनिक विभाग के प्रतिष्ठानों में भी रखे जाते हैं।

हमारी सिफारिश है कि सेवावधि बढ़ाने अथवा पुन नियुक्त करने की एक शर्त यह होनी चाहिये कि सम्बद्ध व्यक्ति की ईमानदारी और निष्ठा-विषयक अच्छी प्रतिष्ठा रही है। यदि यह शर्त पूरी न होती हो तो सेवावधि बढ़ाने अथवा पुन नियुक्ति के लिए सम्बद्ध व्यक्ति को योग्य नहीं समझना चाहिये।

५. भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बैठकाने की बात करने से पर्याप्त हानि होती है। ऐसी बातचीत का होना तभी कम हो सकता है, जबकि कोई ऐसा अभिकरण हो जिसके पास सही शिकायतवाला आदमी इस आश्वासन के साथ पहुँच सके कि यदि उसकी शिकायत सही है तो उसकी पूर्ण सुरक्षा की जायेगी और तुरन्त तथा उपयुक्त कार्यवाही होगी। भ्रष्टाचार, उत्पीडन, परेशानी आदि से सम्बन्धित शिकायतों के मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और सतर्कता सगठन (विजीलेम ऑर्गेनाइजेशन) को इस आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिये। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि सही शिकायत करने-वाले को इस सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये कि उसे परेशान नहीं किया जा सकेगा अथवा कोई उसकी हजामपट्टी नहीं कर सकेगा। गृह मन्त्रालय को इस बारे में अपनी विशेष जिम्मेवारी समझनी चाहिये।

६. उन सभी मन्त्रालयों/विभागों में पूछताछ-सह-स्वागत कार्यालय होने चाहिये, जिनका काम लायसेम्/परमिट से सम्बद्ध हो और जिनमें प्राय जनता जाती-आती रहती है। सभी दर्शकों को स्वागत कार्यालय में रखे गये रजिस्टर में अपने नाम लिखने चाहिये और अपने आने के प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिये।

७. सूचना-विक्रय को रोकने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये। ऐसे मामलों में भी अनावश्यक गोपनीयता का रखा जाना जहाँ वैसा करना आवश्यक नहीं है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार का एक कारण है। इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट विभेद किया जाना चाहिये कि किस प्रकार की सूचना ‘गोपनीय’ समझी जाय तथा किस प्रकार की जनता को मुक्त रूप से उपलब्ध की जा

सकती है। द्वितीय वर्ग की सूचना जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहे वह उस काम के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/प्रतिष्ठान में किसी विशिष्ट अधिकारी तक पहुँचने तथा जो कुछ उसे चाहिये वह प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिये।

हमें बताया गया कि लायसेंस/परमिट आदि प्राप्त करने के लिए जो फार्म भर कर पेश करने पड़ते हैं उनकी प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती हैं। तकावी, सिमेण्ट तथा इस्पात आदि के लिए आवेदन पत्रों के मामले में इस प्रकार की कठिनाई अधिक आनेवाली है। जो मामले केन्द्रीय सरकार निबटाती है उनके मामलों में केन्द्र प्रणामित क्षेत्रों को छोड़ कर अन्यत्र कठिनाइयाँ नहीं आनेवाली हैं। इस प्रकार की कठिनाइयों को जिस किसी हद तक वे हों, दूर करना वाञ्छनीय है। इसलिए हमारी सिफारिश है कि मुफ्त में अथवा कीमत ले कर फार्मों की आसानी से उपलब्धि हो सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये।

सत्यनिष्ठा पर गोपनीय रिपोर्ट

फिलहाल प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में एक 'खाना' होता है जिसमें प्रवर अधिकारी उक्त कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ लिखता है। लेकिन मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत प्रवर अधिकारी के पास अपने सहायक की सत्यनिष्ठा पर शक करने के कोई उपयुक्त कारण हो तो भी किसी प्रमाण के अभाव में उक्त खाना-पूर्ति करना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए यह एक सामान्य पद्धति है कि उस सम्बन्ध में कोई पक्की बात नहीं लिखी जाती। हमारी सिफारिश है कि वैसे मामलों में जहाँ रिपोर्ट देनेवाला अधिकारी सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में निश्चित रिपोर्ट देने की स्थिति में न हो तो उसे वह खाना बिना भरे ही छोड़ देना चाहिये तथा जिसके सम्बन्ध में वह रिपोर्ट दे रहा है उसकी सत्यनिष्ठा पर सन्देह का उसके पास कोई कारण हो तो वैसी अवस्था में अपने सन्देह के कारणों का उल्लेख करते हुए उसे गुप्त रिपोर्ट

देनी चाहिये। इस प्रकार की गुप्त रिपोर्ट प्राप्त करने-वाले अधिकारियों अथवा सरकार को चाहिये कि रिपोर्ट की सही स्थिति का पता लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये।

बड़ी सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद २० दिसम्बर १९६३ को हमने 'सेवा निवृत्ति के पश्चात् सरकारी व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियुक्तियों स्वीकार करने' के प्रश्न पर प्रतिवेदन पेश किया था। उसमें हमने सिफारिश की है कि इस सम्बन्ध में परिपूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिये कि सरकारी व्यक्ति सेवा-निवृत्ति के दो वर्ष बाद तक किसी भी निजी व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई नियुक्ति स्वीकार न करे। हमारे विचार से, यदि कोई इस प्रकार की धारणा हो कि उच्च प्रशासनात्मक श्रेणियों और निजी निगम विभाग के बीच किसी प्रकार की माठ-गाठ, भागीदारी, हित-साधकता अथवा दुरभिसन्धि है, तो उसे दूर करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार की धारणा से, फिर चाहे वह न्याय-सगत हो अथवा नहीं, न केवल जन-सेवा की प्रतिष्ठा पर ही आघात आती है, बल्कि सामाजिक वातावरण पर भी उसका असर पड़ता है।

उन व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक उपाय अपनाना, जो आदतन सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट करते हैं, दूसरी तरफ से बुराई की जड़ काटना है। हम इस विचार का तहेदिल से समर्थन करते हैं कि अत्यधिक मात्रा में काले बाजार के रुपये का होना—जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है—भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार का धन अनेक प्रकार से अर्जित किया जाता है। उदाहरणार्थ, कर की चोरी, तस्करी व्यापार, अचल सम्पत्ति और शेयरो तथा स्टॉक सम्बन्धी सट्टेबाजी, हिसाब-किताब में बिना किसी उल्लेख के आशिक अथवा पूर्ण रूप से शुल्क और भूति के रूप में नकद प्राप्त करना, लायसेंस और परमिटों का व्यापार, मूल्य से ज्यादा अथवा कम का बीजक बनाना आदि। इन प्रश्नों पर

विस्तृत रूप से विचार कर सकना हमारे लिए सम्भव नहीं बन पड़ा है। लेकिन हम कुछ सुझाव देने का साहम कर सकते हैं।

आय कर अधिनियम क अन्तर्गत गोपनीयता

हम सोचते हैं कि आय कर प्रतिवेदनो और कर निर्धारणो को गोपनीय समझने का कोई औचित्य नहीं है। हम देखते हैं कि आय कर अधिनियम, १९६१ में गोपनीयता विषयक प्रावधानो में कुछ ढिलाई की गयी है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। कुछ अन्य विकसित देशो में आय कर विवरणी और निर्धारण गोपनीय नहीं समझे जाते एवम् प्रकाशित किये जाते हैं। हम समझते हैं कि इस प्रकार की विवरणियो और निर्धारणो के प्रकाशन से व्यापार और धधो में लगे उन व्यक्तियो पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा, जो आय-कर की चोरी करने के लिए गोपनीयता विषयक प्रावधानो का लाभ उठाने की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सवेदनशील होते हैं और चूँकि आय-कर के रूप में दी गयी रकम व्यापार अथवा धधे में उनके स्थान का प्रतिबिम्ब प्रकट करती है, इसलिए यदि उनके जितना कमान का विश्वास है उससे कम आय पर आय-कर निर्धारित होता पाया गया, तो अपने साथियो की नजरों में गिरने अथवा अपने प्रतिस्पर्धियो को एक सुराग हाथ लग जाने के डर से वे ठोस रूप से प्रतिनिवृत्त होंगे। हमें यह जान कर खुशी हुई कि १९६४ के वित्त विधेयक में तत्सम्बन्धी कुछ प्रावधानो की व्यवस्था की जा रही है।

अभिहस्तातरण-पत्रों में दर्ज कीमत से पर्याप्त अधिक मूल्य पर सम्पत्ति की खरीद और बिक्री करना, केन्द्रीय सरकार को आय-कर तथा अन्य करों के सम्बन्ध में और राज्य सरकार को मद्रा-शुल्क के सम्बन्ध में धोखा देने का तरीका है एवम् काले बाजार की रकम के हस्तातरण की यह एक सहज पद्धति है। यदि किसी प्रकार केन्द्रीय और राज्य सरकारों अथवा इसी उद्देश्य से बनाये गये किसी विशेष निगम को हस्तक्षेप करने तथा उल्लिखित मूल्य पर सम्पत्ति प्राप्त करने की, अथवा यह समझा जाय

कि सम्पत्ति का जान-बूझ कर कम मूल्य रखा गया है तो कुछ कम मूल्य पर भी प्राप्त करने की, शक्ति दे दी जाय तो, चोर बाजारी के धन पर यह एक भारी प्रहार होगा।

इसी प्रकार मकान किराये पर देने के लिए 'पगडी' अथवा 'नजराना' लेने की आदत भ्रष्टाचार का एक स्रोत है। इस सम्बन्ध में कुछ बहुत ही कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हम समझते हैं कि इस प्रकार की गैर कानूनी 'पगडी' न केवल मकानों और 'फ्लेटो' के मालिक, बल्कि किरायेदार भी लेते हैं, जो नाम मात्र के रूप में तो स्वयम् किरायेदार होते हैं, लेकिन वास्तव में अपने किराये का मकान दूसरों को किराये पर दे देते हैं।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क

हम पहले ही 'बिचवहों' और 'दलालों' का जिक्र कर चुके हैं। स्पष्टतः इनमें व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सही प्रतिनिधि शामिल नहीं हैं। इस सम्बन्ध में हमारी सिफारिशें इस प्रकार हैं

१ किसी भी अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिये जो किसी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान या व्यक्ति की तरफ से काम करने का दावा कर रहा हो, जब तक कि वह उस सम्बन्ध में उपयुक्त रूप से प्रत्यायित न हो और सम्बद्ध विभाग ने उसे उस रूप में स्वीकार न कर लिया हो। इस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनाने से ऐसे व्यक्ति दूर ही रह जायेंगे जिनका भूत अच्छा नहीं रहा हो अथवा जिनकी पैठ यानी प्रतिष्ठा अच्छी न हो। तथापि, किसी फर्म के मालिक या प्रबन्धक आदि अथवा स्वयम् आवेदक द्वारा अधिकारियों से सम्पर्क साधने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

२ प्रत्यायित प्रतिनिधियों तक को भी एक विशिष्ट स्तर से नीचे के अधिकारियों से नहीं मिलने देना चाहिये। प्रत्येक सगठन में सगठन के कार्यों, काम की प्रकृति और परिसीमा तथा सगठन के ढाँचे को ध्यान में रख कर इस प्रकार के स्तर का निर्धारण किया जाय। तथापि, उन स्तरों पर अनुमित सम्पर्क सीमित रखने में सावधानी

वरती जाय, जहाँ भ्रष्टाचार की गुजाइश कम हो। इसका तात्पर्य कभी-कभी यह भी हो सकता है कि सहायक अधिकारियों के स्तर पर सम्पर्क साधने की अनुमति ही न दी जाय।

३ प्रत्यायित प्रतिनिधियों से की गयी सभी मुलाकातों का किमी रूप में रिकॉर्ड रखने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

४ प्रत्येक विभाग में एक ऐसा प्रवर अधिकारी होना चाहिये, जिसके पास यदि किसी आवेदक के मामले में अनावश्यक विलम्ब हो रहा हो तो, वह पहुँच सके।

विभाग द्वारा प्रत्यायित और स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सलाह-मशविरे से एक उपयुक्त कार्य-प्रणाली तैयार करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को प्रत्यायित करने से पहले उसके भूत-कृत्यों की, यदि सम्भव हो तो, जाच की जानी चाहिये। जो व्यक्ति किसी मुस्थापित प्रतिष्ठान में नियुक्त न हो, जोकि उसके सम्पर्क और कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा, उसे किमी भी अवस्था में स्वीकृत न किया जाय।

मुलाकातों का विवरण

यह भी वाछनीय है कि निर्धारित श्रेणियों के अधिकारी, जिनका इन प्रतिनिधियों के साथ काम पड़ता है, पजीकृत प्रतिनिधियों के साथ उनकी जो मुलाकाते और चर्चाएँ हों, उनका नियमित रोजनामचा रखे, फिर चाहे मुलाकात तथा वार्तालाप कार्यालय में हो अथवा घर पर। सामान्य पद्धति यह होनी चाहिये कि इस प्रकार की मुलाकाते कार्यालय में हों, और यदि वे घर पर हों तो कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिये। जिस काम अथवा चर्चा का विवरण न हो उसे अनियमित व्यवहार समझना चाहिये और सम्बद्ध अधिकारी के ऊपरवालो को चाहिये कि उस पर वे गम्भीर कदम उठाये।

कम्पनियों और व्यापारियों के लिए यह आवश्यक बना देना चाहिये कि वे अपने खर्च-खाते का विस्तृत हिसाब रखें। सामान्यतः आय-कर अधिकारियों को इस प्रकार के खातों का विश्लेषण करना चाहिये।

लेकिन जब कभी कोई आय-कर अधिकारी यह महसूस करे कि रकम उच्च अधिकारियों को खुश करने अथवा अन्य किसी ऐसे काम के लिए खर्च की गयी है जिसका कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलता तो उसका यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह यह मामला सम्बद्ध विभाग के सतर्कता अधिकारी के पास पेश करे। मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत इस प्रकार की जानकारी देने के रास्ते में यदि कोई कानूनी कठिनाई आती हो तो, उसे दूर किया जाना चाहिये। आय कर विभाग, सतर्कता अधिकारियों और सेण्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन के मध्य निकट सहकार से ही प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार के सहकार की यदि सार्वजनिक जानकारी हो तो वह एक अच्छा निवारक उपाय होगा।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में विवेकपूर्ण और प्रभावशाली प्रचार कार्य से बड़ी सहायता मिल सकती है। इस प्रकार के प्रचार में एक तरफ अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण देने से बचना चाहिये कि अमुक मामला जरूरत से अधिक सामान्य है, तो दूसरी ओर जनता को विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है तथा यह कि वह उन्हें समाप्त करने में कृत-सकल्प है। गृह मन्त्रालय में एक ऐसा अनुभाग खोलना वाछनीय होगा, जिसमें प्रभावशाली प्रचार-प्रसार के उपाय खोज निकालने के लिए आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय और फिल्म अनुभाग के प्रतिनिधि हों। समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों का अनुकरण करना है वे इस प्रकार हैं

दोषी का भण्डाफोड़

खोजबीन करते वक्त अथवा विभागीय जाच के दौरान किसी प्रकार का प्रचार नहीं होना चाहिये, लेकिन जिन मामलों का परिणाम पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति हो उनका व्यापक प्रचार किया

जाना चाहिये। न्यायालय में चलनेवाले मामलों में महत्वपूर्ण मुकद्दमों की कार्रवाई आम तौर पर पत्रों में आयेगी। जरूरत इस बात की है कि जो व्यक्ति मामलों का सम्पादन करे उन्हें सही तथ्य और तर्क उपलब्ध करवाये जाये। प्रस्तावित अनुभाग को आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिये। ऐसे खास-खास मामलों के सामयिक सक्षेप, उदाहरणार्थ त्रैमासिक सक्षेप, पत्रों को उपलब्ध करवाये जाये, जिनकी विभागीय जांच हुई हो अथवा न्यायालयों में मुकद्दमा चला हो। यह भी अपेक्षा की जा सकती है

कि सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन को, जो समद में प्रस्तुत किया जायेगा, समाचार पत्रों आदि में व्यापक स्थान दिया जायेगा।

वास्तव में एक ऐसा सामाजिक वानावरण विकसित करना सर्वाधिक निवारक उपाय है, जिसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति, तब तक सत्यनिष्ठा का मार्ग छोड़ कर भ्रष्टाचार का पथ नहीं अपनायेगा जब तक कि उसका पूर्णतः नैतिक पतन ही न हो गया हो।

बम्बई के प्रोफेसर दातवाला ने प्रन्यासिता का एक सरल और व्यावहारिक सूत्र प्रस्तुत करके भेजा था। गांधीजी के सम्मुख उसे रखा गया, जिसमें उन्होंने कुछ सशोधन किये। अंतिम मसविदा, सगोचित रूप में, इस प्रकार है :

१. प्रन्यासिता, वर्तमान पूँजीवादी समाज-व्यवस्था को समानतापूर्ण समाज-व्यवस्था के रूप में परिणत करने का एक साधन है। यह पूँजीवाद को प्रश्रय नहीं देता, बल्कि वर्तमान स्वामी वर्ग को स्वयम् सुधर जाने का एक अवसर प्रदान करता है। इसके मूलाधार में यह विश्वास है कि मानव-स्वभाव कभी भी सुधार से परे नहीं है।
२. यह सम्पत्ति पर निजी स्वामित्व के अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करता, सिर्फ उस अवस्था को छोड़कर जब कि समाज अपने कल्याण के लिए स्वयम् उसकी आज्ञा दे दे।
३. स्वामित्व तथा सम्पत्ति के उपयोग के सम्बन्ध में वैधानिक नियमों को यह परे नहीं करता।
४. इस प्रकार राज्य-नियमित प्रन्यासिता के अंतर्गत व्यक्तिविशेष अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए या समाज हित की अवहेलना करके निजी सम्पत्ति रखने या उसका उपयोग करने में स्वतंत्र न होगा।
५. ठीक उसी प्रकार, जैसा कि एक अच्छे जीवन-यापन के लिए न्यूनतम जीवन वेतन निर्धारित करने का प्रस्ताव है, समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए उच्चतम आय की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये। इस न्यूनतम और उच्चतम आय के बीच का विभेद विवेकपूर्ण, समानतापूर्ण और समय-समय पर परिवर्तन योग्य होना चाहिये, ताकि विभेदों को विछिन्न करने की प्रवृत्ति का विकास हो।
६. गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का स्वरूप सामाजिक आवश्यकता के अनुसार होगा, न कि व्यक्तिविशेष की तुल्यकामिजाजी या लोभ के अनुसार।

इस सूत्र को प्रकाशन के लिए समाचारपत्रों को देने का निर्णय किया गया। किन्तु फिर से विचार करने पर ऐसा महसूस किया गया कि प्रकाशन से पहले इसे श्री धनश्याम दास बिडला को दिखा दिया जाय। वे प्रन्यासिता के सिद्धांत के कुछ पक्ष में थे। इसलिए एक प्रति उनके पास भेज दी गयी। उन्होंने उसका स्वागत किया, किन्तु राय दी कि सूत्र के प्रकाशन के साथ ही कहीं सारे प्रयासों का आदि-अंत एक साथ ही न हो जाय, इसलिए अपने साथी-पूँजीपतियों से उन्हें चर्चा कर लेने दी जाय और उसके बाद ही मसविदे के प्रकाशन के साथ-साथ उनकी सहमति की घोषणा भी हो जाय।

अखाद्य तेल से विकेंद्रित साबुन उत्पादन

सुभाष चन्द्र सरकार

साबुन उद्योग के विकास की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए हम बात पर विचार करना समीचीन होगा कि क्या विकेंद्रित इकाइयों को किसी विशेष किस्म के साबुन का उत्पादन कार्य नहीं सौंपा जा सकता, ताकि बड़े और छोटे पैमाने की इकाइयों के मध्य असमान स्पर्धा को कम से कम किया जा सके।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्रम में विकेंद्रित साबुन उद्योग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें साबुन बनाने के लिए यथा संभव अखाद्य तेल का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। ऐसा करने पर जोर देने के ठोस कारण हैं।

प्रथम, खाद्य के रूप में इस्तेमाल करने हेतु काफी मात्रा में खाद्य तेल बचाया जा सकता है। तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक वानस्पतिक तिलहन की माग, आय में घट-बढ़, प्रतिव्यक्ति उपभोग और आबादी में वृद्धि को भी ध्यान में रखते हुए, अन्दाजन एक करोड़ तीस लाख टन की थी। इस माग की तुलना में छ मुख्य तिलहन फसलों— मूँगफली, तिल, राई, सरसों, तिली, और अण्डी— का सम्मिलित उत्पादन लक्ष्य तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में ९८ लाख २० हजार टन अनुमानित था और इस प्रकार वानस्पतिक तिलहन की माग और पूर्ति के बीच काफी अन्तर रह गया था। उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्रति व्यक्ति दो औंस दैनिक खपत, जोकि प्रत्येक वयस्क की तेल सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकता मानी गयी है, के आधार पर वस्तुतः कमी तो अब भी व्याप्त है ही। यदि साबुन बनाने में दिनोदिन अखाद्य तेल की मात्रा बढ़ायी जाय तो लोगों के लिए काफी मात्रा में खाद्य तेल की बचत की जा सकेगी। द्वितीय, अखाद्य तिलहन के उपयोग से, जोकि अभी करीब-करीब बेकार ही जाते हैं, उत्पादन

बढ़ाने में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग हो सकेगा और इससे काफी लोगों को लाभदायक रोजगारी मिलेगी।

उपलब्धि

खाद्य तेल की माग और पूर्ति के सम्बन्ध में स्थिति का परीक्षण करते हुए योजना आयोग की प्राकृतिक श्रोत-सम्बन्धी समिति ने साबुन उत्पादन में नारियल तेल के बदले महुआ, नीम और करज जैसे अखाद्य तेलों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। इण्डियन सेण्ट्रल आयलसीड्स कमेटी के अध्यक्ष ने अखाद्य और गौण तेल के विकासार्थ एक विशेष समिति का गठन किया है। विशेष समिति की सिफारिशों के अनुसार इण्डियन सेण्ट्रल आयलसीड्स कमेटी में ही एक अलग विभाग राज्य सरकारों के वन और कृषि विभागों, तिलहन एकत्र करनेवाले अभिकरणों, अनुसंधानशालाओं और तेल का उपयोग करनेवाले उद्योगों जैसे विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है। इण्डियन सेण्ट्रल आयलसीड्स कमेटी ने देश की विभिन्न रसायन प्रयोगशालाओं में अखाद्य तिलहन पर तकनालाजीकल अनुसंधान करने हेतु कई परियोजनाएँ प्रवर्तित की हैं। इन परियोजनाओं पर तीसरी पंच वर्षीय योजना में करीब ३ लाख ५० हजार रुपये खर्च होंगे।

देश में उपलब्ध प्रमुख अखाद्य तिलहन है नीम (अजाडिरैंक्टा इण्डिका), महुआ (बेसिया लेटिफोलिया),

करज (पोगामिया ग्लाब्रा), पिलू अथवा खाखन (साल्वाडोरा ओलियोडाइज), पीसा (एक्टीनोडाफने हुकेरी), उन्दी (कैलोफायलम इनोफायलम), मरोती (हिडनोकार्पल्स विगटियाना), रत्नज्योति (जेंद्रोफा यूफारबेसिया), कमला (मैलोटेस फिलिपिनेसिस), कोकम (गार्मिनिया इण्डिका), नहोर (मेमुआ फेरिया)। इनमें से कई तिलहन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और उनमें १५ से ६० प्रति शत तक तेल की मात्रा पायी जाती है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अखाद्य तिलहनो की वर्तमान प्रति अदाजन करीब दस लाख टन हैं जिसका राज्यवार वितरण इस प्रकार है आन्ध्र प्रदेश-५७,२४४ टन, असम-७८,१७६ टन, बिहार-४,२०० टन, गुजरात-३७,९९० टन, केरल-२,४२५ टन, मध्य प्रदेश-७९,७१२ टन, मद्रास-१,००,०७२ टन, महाराष्ट्र-८०,४०८ टन, मैसूर-२७,६६२ टन, उड़ीसा-५,४११ टन, पंजाब-११,३०५ टन, राजस्थान-६,६०१ टन, उत्तर प्रदेश-९९,७०४ टन, पश्चिम बंगाल-६,४१५ टन। इन तिलहनो से न्यूनतम स्तर पर भी कम से कम २ लाख टन तेल की प्राप्ति की जा सकती है, जबकि १९५७-५८ वर्ष में मिल विभाग में सिर्फ ६१,६७१ टन तिलहन पड़े गये जिस से १९,४४० टन तेल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार साबुन उद्योग में इस्तेमाल के लिए अखाद्य तेल उत्पादन में वृद्धि की काफी गुंजाइश है।

समस्याएँ

साबुन के नियमित उत्पादन हेतु अखाद्य तेल के उपयोग के तीन पहलू हैं (१) तिलहन एकत्रण, (२) तेल निस्सारण, और (३) साबुन निर्माण।

अखाद्य तिलहनो का सग्रह एक समस्या उपस्थित करता है, क्योंकि अखाद्य तिलहनवाले वृक्ष देश में व्यापक रूप से फैले हुए हैं, उनमें से कई तो सुदूर क्षेत्रों में और ६,००० फुट तक की ऊँचाई तक पाये जाते हैं। प्रत्यक्ष है, यदि इन छितरे क्षेत्रों से अखाद्य तिलहन बड़ी मात्रा में सग्रह कर शहरों में केन्द्रीय

उत्पादन केन्द्रों को भेजे जाये तो बहुत अधिक परिवहन खर्च बैठेगा। परिवहन की समस्या अशत हल की जा सकती है, यदि उन इलाकों में, जिन के निकट काफी मात्रा में अखाद्य तिलहन उपलब्ध हैं, छोटे-छोटे अखाद्य तेल और साबुन उत्पादन केन्द्र खोले जायें। तिलहन की कमी की समस्या गंभीर भी है, विशेष कर इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके भाण्डारीकरण की उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

फिर, इन अखाद्य तिलहनो से तेल निकालना भी बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः विजली नहीं पायी जाती। अतः पशु-चालित धानियों और हस्त-चालित स्क्रू प्रेस का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए किया जाता है। चूँकि अखाद्य तेल निस्सारण अपेक्षतया एक नवीन कार्य है, अतः तेल निकालने के लिए पर्याप्त धानियाँ प्राप्त करना भी हमेशा सहज काम नहीं है।

निस्सारित तेल को साबुन उत्पादन में इस्तेमाल करने के पूर्व प्रशोधित करना होता है, क्योंकि अखाद्य तिलहनो से प्राप्त अपरिशोधित वसा दुर्गन्धपूर्ण, कड़वी और काली होती है।

प्रयास

यह आशा करना उचित नहीं है कि अपने ही बल पर काम करनेवाले छोटे-छोटे उत्पादक अखाद्य तिलहनो के उपयोग में सन्निहित इन गंभीर समस्याओं को हल कर लेंगे। स्पष्टतः इसके लिए एक अखिल भारतीय अभिकरण की आवश्यकता है, जोकि इस नये उद्योग का विकास कार्य सभाले और उद्योग की क्षमता को प्रसारित करे तथा वैज्ञानिक और तकनालाजीकल समस्याओं को हल करने में हर तरह की मदद देने का आश्वासन दे कर, लोगों को यह उत्पादन कार्य अपनाने की प्रेरणा दे। यह कार्य खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा अपनाया गया है, जिसे कि ससद ने ग्रामोद्योगों का विकास करने हेतु विशेष रूप से गठित किया है।

चूँकि साबुन बनाने में अखाद्य तेल का उपयोग करने का मुझाव एक नयी बात है, इसलिए कमीशन ने विभिन्न स्तरों पर सहायता दे कर उद्योग का विकास करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाना आवश्यक समझा है। पिछले वर्षों में जैसे-जैसे उद्योग का विकास हुआ है सहायता पद्धति में भी काफी परिवर्तन हुए हैं और विभिन्न पहलुओं पर जोर भी दिया गया है। अभी तकनीकल मार्गदर्शन देने के अलावा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तिलहन एकत्रण, तेल पेराई और साबुनसाजी के लिए अनुदान और ऋण स्वरूप वित्तीय सहायता भी देता है। तिलहन एकत्रण के लिए कमीशन तीन हजार रुपये पूँजीगत खर्च के लिए देता है, जिनमें से आधे अनुदान रूप होते हैं। तिलहन का स्टॉक जमा करने के लिए दिया गया ऋण केन्द्र द्वारा अनुमानित एकत्रण की वास्तविक जरूरत तक दिया जाता है। उपदान स्वरूप सहायता एकत्रित तिलहन के कुल मूल्य के ५ प्रति शत तक या कम से कम ३०० रुपये प्रति वर्ष, प्रथम तीन वर्षों के लिए, दी जाती है तथा चौथे व पाचवें वर्ष में क्रमशः तीन और दो प्रति शत। इसके अलावा गोदाम बनाने के लिए १५ हजार रुपये तक सहायता दी जाती है जिसमें से ५० प्रति शत अनुदान होता है और यह तिलहन केन्द्रों को दिया जाता है। तेल पेराई केन्द्र को नौ हजार रुपये की सहायता दी जाती है जिसमें से ३,००० रुपये अनुदान, ३,००० पूँजीगत खर्च, और ३,००० रुपये संचालन पूँजी ऋण के लिए होते हैं। फिर कमीशन प्रत्येक केन्द्र के प्रबन्धक के वेतन भुगतान के लिए भी (पहले दो वर्षों में ६० रुपये प्रति माह, तीसरे वर्ष में ४५ रुपये प्रति माह और चौथे एवं पाचवें वर्ष में ३० रुपये प्रति माह) सहायता देता है।

अखाद्य तेल से साबुन बनाने के लिए साबुन केन्द्रों की तीन श्रेणियाँ हैं ए, बी और सी, जिनकी स्थापना के लिए ९,००० रुपये तक आर्थिक सहायता पूँजीगत खर्च के लिए दी जाती है, जिसमें से ५० प्रति शत अनुदान होता है। संचालन पूँजी भी दी जाती

है जोकि कुल उत्पादन-विक्री पर निर्भर करती है। केन्द्र के प्रकार के अनुसार कमीशन एक रसायनज्ञ की तनख्वाह भी देता है, जोकि प्रथम वर्ष के लिए १५० रुपये प्रति माह होती है तथा बाद के ३ वर्षों में धीरे-धीरे कम होती जाती है। इस के अतिरिक्त केन्द्रों को विक्री बढ़ाने के लिए, जोकि निर्धारित लक्ष्य से अधिक विक्री करते हैं, अतिरिक्त विक्री पर ४२ रुपये प्रति टन की दर से विक्रय-उत्प्रेरणा दी जाती है।

कमीशन केन्द्रों को अपने उत्पादन की विक्री बढ़ाने हेतु अनुदान रूप में सहायता देता है। दो वर्षों के लिए विक्रेता के वेतन स्वरूप ६०० रुपये और पूँजीगत खर्च के लिए ६०० रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं।

प्रशिक्षण

अखाद्य तिलहन के एकत्रण और भाण्डारीकरण के उचित तरीके सिखाने के लिए कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। गलत ढंग से एकत्रण करने और दोषपूर्ण भाण्डारीकरण से बहुत-से तिलहनो का नुकसान हो सकता है तथा उनकी आर्थिक उपयोगिता भी कम हो सकती है। फिर भी, चूँकि यह उद्योग विकेन्द्रित आधार पर अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है, अतः वैसे कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकें। दिनांक ३० जनवरी १९६३ को महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिला स्थित मोहोल में अखाद्य तेल और साबुन उद्योग के लिए एक केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्था का उद्घाटन किया गया, जोकि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत चल रही है।

तिलहन एकत्रण और साबुनसाजी का काम करने के लिए उन क्षेत्रों में जहाँ कि अब भी कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है, कई विस्तार केन्द्रों और मार्गदर्शी इकाइयों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों के संगठन की जिम्मेदारी अखिल भारत अखाद्य तेल उद्योग सघ को सौंपी गयी है जिसका प्रमुख कार्यालय पूना में है।

चन्द क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन स्वयम् ही ऐसे केन्द्रों की स्थापना करता है।

तिलहन एकत्रण, उनका प्रशोधन और तेल पेरार्ई करना तथा अखाद्य तेल से साबुन बनाना सिखाने के लिए कमीशन विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र चलाता आ रहा है। प्रशिक्षण अवधि छ माह है। वर्ष १९६२-६३ में सात विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (तिलहन एकत्रण और तेल पेरार्ई) ने ४२ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जबकि १३ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (साबुनसाजी) ने अखाद्य तेल से साबुन बनाने में ६९ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। स्कूली इकाइयों में प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षकों को चार उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षित किया गया।

कमीशन ने यह उद्योग १९५३-५४ में अपने हाथ में लिया। उद्योग को चलाने के लिए कोई सगठनात्मक स्वरूप सामने नहीं था। अतः सभी स्थानों में कमीशन को सगठनों का निर्माण करना पड़ा। पिछले दस वर्षों में नीचे को मजबूत करने के लिए कमीशन

(४७,७३५ रुपये मूल्य का १,५७,००० किलोग्राम) का स्थान था। अखाद्य तिलहन की पूर्ति करनेवाले मुख्य राज्य थे— मैसूर, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश। वर्ष १९६२-६३ तक ६२७ केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी, जिनमें से १४९ केन्द्रों को खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक सहायता दी तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों ने ४७८ केन्द्रों को, इनमें से ३३९ सहकारी समितियाँ हैं तथा २८८ सन् १८६० के समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियाँ। नीचे दी गयी तालिका में विभिन्न श्रेणियों के सगठनों द्वारा चलाये जानेवाले केन्द्रों का विवरण है।

अकेले १९६२-६३ वर्ष में ९३ हजार व्यक्तियों को तिलहन एकत्रण कार्य में रोजगारी मिली और उनमें पारिश्रमिक स्वरूप १७ लाख रुपये बाटे गये।

इस विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत १९६२-६३ वर्ष में अखाद्य तेल का कुल उत्पादन २०,०६,४४८ रुपये मूल्य का ११,३०,४५७ किलोग्राम हुआ जिसमें

तालिका

कमीशन द्वारा सहायित अखाद्य तेल साबुन उत्पादन केन्द्रों का वितरण

वर्ष	खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रत्यक्ष सहायित	राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों द्वारा सहायित	सहकारी समितियाँ	पंजीकृत समितियाँ (सन् १८६० के समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)	कुल
१९५८-५९	११९	२५१	१८०	१९५	३७५
१९५९-६०	१३४	३४३	२४१	२३६	४७७
१९६०-६१	१३८	४००	२८०	२५८	५३८
१९६१-६२	१४६	४४५	३०७	२८४	७६१
१९६२-६३	१४९	४७८	३३९	२८८	६२७

द्वारा काफी काम किया गया। वर्ष १९६२-६३ में १८ लाख ५१ हजार रुपये मूल्य के ८६,१४,००० किलोग्राम अखाद्य तिलहन एकत्रित किये गये। इनमें से १०,६७,४७९ रुपये मूल्य की ६५,३४,००० किलोग्राम निम्बूरियाँ थी। उसके बाद महुआ (६,४५,१६० रुपये मूल्य का १५,०३,००० किलोग्राम) और करज

१,०३४ व्यक्तियों को पूर्ण-कालीन और १०,२१९ व्यक्तियों को अश-कालीन रोजगारी मिली। पूर्णकालीन कर्मियों की कुल वार्षिक आय २,२९,३३९ रुपये और अश-कालीन कर्मियों की १,०५,०६१ रुपये रही।

वर्ष १९६२-६३ में साबुन उत्पादन में ३१७ केन्द्र लगे थे जिनमें से १८९ सन् १८६० के समिति

पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियाँ थी और बाकी १२८ सहकारी समितियाँ। इन केन्द्रों ने १९६२-६३ वर्ष में कुल ५० लाख रुपये मूल्य का ३७,३४,००० किलोग्राम साबुन का उत्पादन किया जोकि पिछले वर्ष के उत्पादन में २३ प्रतिशत अधिक था। उस वर्ष ५१ लाख रुपये मूल्य के ३४,५५,००० किलोग्राम साबुन की बिक्री हुई। साबुन उत्पादन कार्य में ७८५ व्यक्तियों को पूर्ण कालीन और ४,०८४ व्यक्तियों को अर्ध-कालीन रोजगारी मिली और उनकी आय क्रमशः ४,६७,४६५ रुपये और ५९,८०२ रुपये रही।

उत्पादन में लगे ३१७ केन्द्रों में से १७६ ने निर्धारित लक्ष्य के ५० प्रतिशत से अधिक की पूर्ति की। इन १७६ केन्द्रों में से १०२ पंजीकृत समितियाँ थी और ७४ सहकारी समितियाँ।

अखाद्य तेल से साबुन बनाने के कार्य में पंजाब, गुजरात और मद्रास राज्य अग्रणी रहे।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्रम में माध्यमिक विद्यालयों में अखाद्य तेल से साबुन उत्पादन करने का कार्य आरम्भ करना भी शामिल है। वर्ष १९६२-६३ में ३० स्कूलों इकाइयों चल रही थी। उनमें से २१ ने साबुनसाजी के २२५ प्रदर्शन किये तथा ९८८ पुराने और ५,०११ नये विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया।

जेलों में बन्धियों को साबुन बनाना सिखाने की योजना भी है। जेलों के लिए स्वीकृत २९ साबुन उत्पादन केन्द्रों में से १० की स्थापना १९६२-६३ में की गयी। उस वर्ष के अन्त तक मैसूर राज्य के बेलारी केन्द्रीय जेल के साबुन केन्द्र ने उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया।

विकेन्द्रित साबुन उद्योग मुख्यतः खाद्य तिलहनो का उपयोग करता है। तथापि इसे कुछ अंश में नारियल तेल और कास्टिक सोडा का भी इस्तेमाल करना होता है।

नारियल तेल और कास्टिक सोडा उचित दर पर प्राप्त करने में उद्योग में कठिनाई महसूस हो रही है, क्योंकि ये विकेन्द्रित इकाइयों लम्बे अरसे के लिए कच्चा माल भाण्डारित करने योग्य नहीं है। इन कच्चे मालों के खरीदने में बड़े पैमाने के निर्माताओं की स्पर्धा में वे अपने को घाटे की अवस्था में पाती हैं।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की एक नीति के अनुसार ग्रामोद्योगों के विकासार्थ सहायता तरजीहें सहकारी समितियों और पंजीकृत समितियों को दी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ कि अनपढ़ और उत्पादन की आधुनिक विधियों से अनभिज्ञ लोगों की संख्या अधिक है, औद्योगिक सहकारी समितियों के गठन में आनेवाली कठिनाइयों सर्वविदित हैं और इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। उन क्षेत्रों में वित्त, तकनीक ज्ञान और प्रबन्धकीय दक्षता उपलब्ध नहीं है। कमीशन वित्तीय और तकनीक सहायता दे सकता है, प्रबन्धकीय प्रतिभाओं को स्थानीय रूप से प्राप्त करना है। यह कोई सहज कार्य नहीं है।

फिर, बिक्री की भी समस्या है। विकेन्द्रित इकाइयों द्वारा जोकि अखाद्य तेल का इस्तेमाल करती हैं, मिल विभाग के आधुनिक साबुन उद्योग से खुले बाजार में प्रतियोगिता करना तो संभव है ही नहीं।

यह तो मानी हुई बात है कि देश में विकेन्द्रित साबुन उद्योग की क्षमता सीमित है। अतः संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम के लिए दिया गया सुझाव निरासन्न होना होगा। फिर भी, साबुन उद्योग के विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करना बहुत अच्छा होगा कि क्या विकेन्द्रित इकाइयों को खास किस्म के उत्पादन का कार्य नहीं सौंपा जा सकता, ताकि बड़े पैमाने और छोटे पैमाने की इकाइयों के बीच की प्रतियोगिता को कम किया जा सके।

(इकनॉमिक टाइम्स से साभार)

पुस्तक समीक्षा

दि ट्रायबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन : ऐन
ऑटोबायोग्राफी, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई,
१९६४, पृष्ठ बारह+३५६, मूल्य २० रुपये।

देश की आदिवासी जनता में दिलचस्पी रखनेवालों को
स्व डा वेरियर एल्विन का परिचय देने की आवश्यक-
कता नहीं। आदिवासी जीवन और संस्कृति को समझने
के प्रत्येक प्रयास के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है अर्थात्
इस क्षेत्र में हर कदम पर उनका नाम आता है।
आलोच्य पुस्तक डा एल्विन की विवरणात्मक आत्म-
कथा है, जिसे उन्होंने अपने देहावसान के पहले पूरा कर
दिया था। यह पुस्तक न सिर्फ डा एल्विन के जीवन
और कार्यों पर बल्कि भारत के आदिवासी जीवन पर
इस बात का विशेष उल्लेख करते हुए प्रकाश डालती है
कि पिछले तीस वर्षों में उनकी अवस्था सुधारने हेतु
क्या-क्या प्रयास किये गये हैं। जिस प्रकार डा एल्विन
का जीवन बहुमुखी था, उसी प्रकार उनकी जीवनी
भी विविध प्रमग प्रस्तुत करती है। उनका जीवन
मानवीयता और समझबुझ से भरपूर था। डा एल्विन
में मित्र बनाने की असाधारण क्षमता थी और वे बहुतों
के प्रिय थे।

गांधी और टैगोर के सम्बन्ध में उनके विचार,
जिनका प्रत्यक्षत उनके जीवन पर बहुत
प्रभाव था, बड़े रुचिकर और विस्तार में
उद्धृत करने योग्य है। उदाहरणार्थ “ईसाई
धर्म के बाद गांधी आये। अन्य लोगों की तरह मैं
गांधीजी के उन उपदेशों यानी विचारों को अपना लेता

हूँ जोकि मुझे अच्छे लगते हैं और बाकी को छोड़ देता
हूँ। गांधी दर्शन के भारत द्वारा परित्याग, जोकि उनकी
मृत्यु के पूर्व ही आरम्भ हो गया, का प्रतीक है—दाह-
संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को तोपगाड़ी
(गन-कर्रेज) पर ले जाना। गांधीवाद की बहुत-
सी बातों को मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया हूँ, विशेष
कर इसका विशुद्धतावादवाला पक्ष, परन्तु इसके साथ
ही उसमें अनेक बातें प्रेरणादायक भी थी। सत्य सम्बन्धी
उनकी शिक्षा का मर्म, क्रोध का प्रेम से शमन करने-
वाला उनका सिद्धान्त और विशुद्धतावाद से अलग उनकी
सादगी आज भी हृदयग्राही लगती है। और, मैं उस
विलक्षण व्यक्तित्व को, जोकि एक साथ ही
प्रेममय और तेजमय था, अथवा जो प्यार
उन्होंने मुझे उस समय दिया जबकि मैं उनके
योग्य बिल्कुल नहीं था, कभी भूल नहीं सकता
और यही कारण है कि आज भी मैं उनका नाम सुन
कर गर्व और हर्षोल्लास महसूस किये बिना नहीं
रह सकता।

“मैं टैगोर से कभी मिला नहीं, यद्यपि उन्होंने मुझे
उसी समय से प्रभावित किया जबकि मैं ऑक्सफोर्ड में
पढ़ता था। एक अजीब बात यह है कि मैं उनकी ओर
सर्व प्रथम उनकी प्रसिद्ध गीताजलि से आकर्षित न होकर
कबीर के दोहों का उनके द्वारा किये गये अनुवाद
से हुआ, और प्राच्य कविता से वह मेरा प्रथम परिचय
था।

“मेरे गामने सदैव मार्ग अर्थात् पक्ष रहे हे— एक
ओर गांधीजी का निर्लिप्त मार्ग और दूसरी ओर

टैगोर का ससार अपनाने का रास्ता। सौन्दर्य, राग और रग में टैगोर के विश्वास में, जबकि भारत में अधिकांश लोग प्रेम से डरते थे परन्तु वे नहीं, मेरे हृदय में बड़ा ही उत्साह से भरपूर प्रत्युत्तर पैदा किया। 'जो भला करना चाहता है वह दरवाजा खटखटाता है, परन्तु जो प्यार करता है उसके लिए दरवाजा खुला है।' टैगोर की हर बात, हर चीज सकारात्मक थी। उन्होंने स्वयम् जीवन को ही कला-कृति बना दिया था। वे आदिवासी सतालो में दिलचस्पी रखते थे और उनसे प्रेरित हुए थे। वस्तुतः मैंने प्रायः यह महसूस किया है कि आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन और नीति-निर्माण कवियों और कलाकारों द्वारा निर्दिष्ट होने चाहिये।

“भारत इसे अपना सौभाग्य मानता है कि स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ते समय, उस नाजुक अवधि में उसे मार्गदर्शन देने के लिए दो-दो व्यक्ति थे— गांधी और टैगोर। गांधी ने लोगों में जोश पैदा किया और उन्हें दृढ़ बनाया और एक बृहत् साम्राज्य से अहिंसात्मक ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए उनके कठोर संदेश उनके अनुगामियों को जागृत करने और उनकी धमनियों में रक्त संचार करने के लिए परमावश्यक थे। परन्तु ललित कला के पक्ष में वे कमजोर थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक गीतों को छोड़ कर अन्य प्रकार की कविता में उनकी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। कला को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने शायद ही कुछ किया हो। जिस हाथ करघा उद्योग के जरिये वे एक सौन्दर्य-ससार का निर्माण कर सकते थे, उसका उपयोग उन्होंने सादे और कोरे वस्त्र बनाने के लिए किया, जिसे आज भी उनके अधिकांश अनुगामी धारण करते हैं, क्योंकि वे भारत को कैदखाने के कपड़े में रख कर हमेशा उसे उसकी हैसियत की याद दिलाते रहना चाहते थे। टैगोर के बिना भारत सूखा और रगविहीन हो गया होता। वह विश्व के सौन्दर्य, मानव जीवन के परमावश्यक गीत तथा वह जिन चीजों का निर्माण करता है उन्हें, भूल

गया होता। टैगोर परिपूर्ण सटीक प्रति-प्रभावी थे और इन दोनों व्यक्तियों का मेल सम्पूर्ण भारत और मेरे लिए तो निश्चय ही बहुत आवश्यक था।”

इस तरह की पुस्तक का पठन वस्तुतः आनन्द-दायक है।

—सुभाष चन्द्र सरकार

बम्बई २६ अगस्त १९६४

★ ★ ★

इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, लेखक आर वी जठार, इन्स्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक रिसर्च, बारवाड, १९६४, पृष्ठ २१९, मूल्य १० रुपये।

मई १९६२ में केन्द्रीय सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने के बाद प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री आर वी जठार को धारवाड स्थित 'इन्स्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक रिसर्च' ने 'भारत में पंचायत राज का विकास' का गवेषणात्मक अध्ययन करने का काम सौंपा। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने, वैदिक युग से लेकर पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना में रूपांतरित होने वाली ग्राम पंचायतों के हाल ही के इतिहास तक, ग्राम पंचायतों के इतिहास तथा विकास का परीक्षण किया है। ऐसा करके उन्होंने तत्सम्बन्धी विभिन्न विवरणों से प्राप्त जानकारी एक स्थल पर जुटाई है। प्रस्तुत प्रकाशन में जिन महत्वपूर्ण सिफारिशों का जिक्र है उनमें 'सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा अध्ययन दल', 'पंचायत राज वित्त अध्ययन दल' तथा 'ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति अध्ययन दल' के प्रतिवेदनो तथा 'भारतीय राज्य प्रशासन सेवाएँ' और 'जिला प्रशासन की समस्याओं पर प्रतिवेदन' में की गयी सिफारिशें हैं।

प्रथम तीन अध्यायों में लेखक उन बातों पर चर्चा करता है प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका, अंग्रेजी शासनकाल में उनका विकास और पंचायतों के स्थापनार्थ संविधानिक निर्देश। चतुर्थ और पंचम अध्यायों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए बलवन्त-राय मेहता समिति के प्रस्ताव तथा प्रत्येक राज्य में उसे

कार्यान्वित करने हेतु अपनाये गये स्वरूप का परीक्षण किया गया है। विभिन्न अधिनियमों में इनमें से प्रत्येक सस्था के लिए सगठनात्मक स्वरूप, शक्ति, वित्त तथा साधन-स्रोतों का जो प्रावधान रखा गया है उस पर भी लेखक ने आवश्यक ध्यान दिया है। अनुवर्ती अध्याय में लेखक ने पचायत राज में सेवाओं की भूमिका, स्वैच्छिक सगठनों, ग्राम सभाओं तथा न्याय पचायतों से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया है। यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र सभ में स्वायत्त शासन सस्थाओं का इतिहास खासा लम्बा है। लेखक ने वर्तानिया स्वीडन, युगोस्लाविया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र सभ की स्वायत्त शासन सस्थाओं का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत प्रकाशन में दिया है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्रायः सभी राज्यों में ग्राम पचायतों के सगठन और विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। हाल ही में बनाये गये पचायत राज कानूनों से प्रशासन-पद्धति में एक महत्वपूर्ण सगठनात्मक परिवर्तन और संविधान तथा पंच वर्षीय योजनाओं में निर्दिष्ट आर्थिक व सामाजिक नीति के मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विभिन्न राज्यों में अपनाया गया पचायत राज सस्थाओं का स्वरूप मोटे तौर पर एक समान है, अन्तर मात्र विस्तृत बातों में ही है। चूंकि उक्त व्यवस्था हाल ही में लागू की गयी है, इसलिए अभी वह अपने शैशव-काल में ही है। जिन राज्यों में उसे पूर्णतः कार्यान्वित किया जा चुका है, उनमें पचायत राज सस्थाओं की कार्यशीलता सम्बन्धी अनुभव और ज्ञान इतना पर्याप्त नहीं है कि हम किसी वैध निष्कर्ष पर पहुँच सकें। बुनियादी तौर पर ग्राम, खण्ड और जिला आयोजन, योजना कार्यान्वय तथा सामाजिक कार्याकल्प के साधन की दृष्टि से पचायत राज में महान सम्भाव्यताएँ हैं। पचायत राज सस्थाओं की वृद्धि और विकास इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि जनता की आवश्यकताओं को समझने के लिए वे किस प्रकार

कितना प्रयास करती हैं तथा समाज के आर्थिक एवम् सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए किस प्रकार वे एक सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन करती हैं।

इस प्रकार के सगठित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड यह है कि विकास के लिए आवश्यक कर लगाने और इकट्ठा करने की उनमें कितनी क्षमता है। राजस्थान में हाल ही में किये गये पचायत राज के अध्ययन से प्रकट होता है कि पचायत समितियों की स्थापना हुए तीन वर्ष हो गये, लेकिन कुल २३२ में से केवल १७५ ने ही कर लगाया। सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सगठित प्रयासों की एक दूसरी कसौटी यह है कि इस नये काम में अपने को लगाने के लिए प्रशासन में कितनी क्षमता है, किस हद तक वह इसमें सफल होता है। सरकारी कर्मचारियों और लोक प्रतिनिधियों के बीच कैसा सम्बन्ध है, इसका यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। यह नहीं कहा जा सकता कि विभिन्न राज्यों के सभी भागों में सही प्रकार के सम्बन्धों का विकास हुआ है और वे स्थापित हो चुके हैं। सरकारी अधिकारियों और लोक-प्रतिनिधियों के कार्य-क्षेत्रों, शक्तियों तथा कर्तव्यों का स्पष्ट प्रतिपादन आवश्यक प्रतीत होता है। पारस्परिक समझ-बूझ और एक-दूसरे की कद्र करने जैसी बातों का विकास केवल इस प्रकार के विवेकपूर्ण प्रयास से ही हो सकता है। लोकप्रतिनिधियों की प्रधान भूमिका यह होनी चाहिये कि वे विकासशील कार्यों में लोक उत्साह तथा जन सहयोग का निर्माण करें। लोक प्रतिनिधियों को ठोस प्राविधिक परामर्श देना और प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत आधार पर अत्यन्त कुशलतापूर्वक कार्यक्रम कार्यान्वित करना सरकारी अधिकारियों का परम कर्तव्य होना चाहिये। अधिकारियों को आवश्यक रूप से ही समुदाय के सफल विकास के लिए समाज की आवश्यकताओं तथा भावनाओं के प्रति और अधिक प्रत्युत्तरगामी बनने की क्षमता अर्जित करनी होगी।

—इन्दिरा अनन्तराम अय्यर

बम्बई १ अगस्त १९६४



महोदय,

अगरत १९६४ के **स्वादी आन्दोलन** में श्री त्रिलोक-नाथ भास्कर द्वारा लिखित 'औद्योगिक सहकारिताएँ और लोकतांत्रिक समाजवाद' में उठाये गये प्रश्नों पर पाठकों के विचार आमंत्रित कर आपने एक अच्छा काम किया है। लेखक द्वारा प्रस्तुत कुछ सुझावों का यदि अनुसरण किया जाय तो फलस्वरूप अन्ततोगत्वा समितियाँ बन्द पड़ जायेंगी और स्वयम् सहकार आन्दोलन ही समाप्त हो सकता है।

लेखक ने प्रश्न उठाया है कि "क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य होना चाहिये, जिनके पास कुछ नहीं है—?" और आगे सुझाव देते हैं कि इस प्रकार की अवस्थाएँ निर्मित करनी चाहिये जो पूँजीपतियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा उपक्रमियों को सहकारिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सके। और, ये ही तो वे तत्व हैं जिन्हें सहकारिताओं के प्रत्येक अंग से बाहर निकाल फेंकना है। विश्व के अनेक देशों में जहाँ शक्तिशाली और स्वस्थ सहकारिता आन्दोलन पनप रहा है हम देखते हैं कि वह इन तत्वों से परिपूर्ण मुक्त है तथा यहाँ तक कि यदि ये तत्व आन्दोलन में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए उल्टा वह उनसे लोहा लेता है। भारतीय सहकारी आन्दोलन में उनके घुस बैठने से वह कमजोर और छिन्न-भिन्न हुआ है। ये तत्व चाहे सरकार हो अथवा

प्राविधिक, सफल पूँजीपति या उनका समूह, सभी अवाञ्छनीय तत्व हैं। ससार भर में सफल सहकारी समितियाँ वे ही हैं जो अपने बल-बूते पर विकसित हुई हैं। इस 'अपने बलबूते' में पूँजी, प्रबन्ध और प्राविधिक कौशल भी शामिल हैं। आज जो सहकारी समितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों को सफलतापूर्वक चुनौती देती हैं, वे ऐसी समितियाँ नहीं हैं कि जिन्होंने विनियोजकों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया हो और अधिकतम अधिलाभ (टिवीडेण्ट) उन्हें दिया हो।

लेखक का कहना है कि कामगारों को समितियों के स्वामित्व, प्रबन्ध और लाभ में हिस्सा देना चाहिए। यह बात तो स्वयम् सहकारिता के विचार के ही विरुद्ध है। स्वामित्व और मुनाफाखोरी एक अर्जनशील समिति की विशेषताएँ हैं। यदि ऐसी समिति एक सुममृद्ध अवस्था भी प्राप्त कर ले तो भी उनका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। एक सही अर्थ में सहकारी समिति की सम्पत्ति उसके सदस्यों की पूँजी नहीं है। यहाँ तक कि यदि लाभ भी हुआ तो उसे उसी स्रोत में और उसी अनुपात में छूट के रूप में वापिस कर दिया जाता है, जहाँ से वह आया है। वरतुत लेखक स्वयम् अपनी बात का विरोध करता है जब वह कहता है कि 'ग्रामदान सच्चा सहकार है जिसमें लोग अपनी मदद के लिए एक-दूसरे की मदद करने की उपयोगिता समझते हैं।' बाहर का कोई भी आदमी यदि उनके लिए किसी रूप

मे कोई उपकार करता है तो वह उन्हें सच्चे सहकार से दूर भगाता है। पूँजीपति इसलिए नहीं फलते-फूलते कि वे बुद्धिमान हैं अथवा उनमें कोई विशेष प्राविधिक श्रेष्ठता या व्यापारिक कुशाग्रता है। सभी प्राविधिक, प्रबन्धकीय और व्यापारिक पक्षों का प्रबन्ध निचले स्तर के लोग करते हैं। पूँजीपति को श्रेय इसलिए मिलता है कि उसके पास मात्र लाभ कमाने के लिए विनियोजन करने हेतु पूँजी है। ये ही व्यक्ति यदि किसी सहकारिता के अन्तर्गत काम करते हैं तो उसे लाभ पहुँचायेंगे। जहाँ तक पूँजी का सवाल है, यूरोप तथा अन्यत्र स्थानों की सही सहकारिताओं का अनुभव बड़ा अच्छा रहा है। उनके पास कभी पूँजी की कमी नहीं पड़ती और कीमती उपक्रमों में विनियोजित पूँजी की भी वे लघु काल में ही पुनर्वाप्ति कर लेती हैं। तब क्यों फिर भारतीय सहकारी समितियों को शोषकों के चंगुल में फसाया जाय ?

सहकार का वास्तविक आधार सदस्यों की 'आवश्यकता' है। और, सहकारिताओं का गठन इस प्रकार की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिये। 'एक ही' मत देने का अधिकार सदस्य को होना चाहिये और कोई सदस्य कितनी पूँजी किसी सहकारिता में लगाता है, इसका मत देने से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। ऐसा करने से यह एक साथ ही 'लोकतंत्र और समाजवाद' दोनों बन जाता है। 'साधन-सम्पन्न' और 'साधन विहीन' की खिचड़ी नहीं होनी चाहिये। वस्तुतः सहकार दर्शन में ही 'वर्ग भेद' का सम्बोधन नहीं है। सहकारी आन्दोलन के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ औद्योगिक सहकारिताओं में स्वामित्व, प्रबन्ध और लाभ में हिस्से की बात शामिल की जाती है तथा वे सहकारिताएँ या तो जाइण्ट स्टॉक कम्पनियों में रूपांतरित हो जाती हैं अथवा स्वेच्छापूर्वक या अनिवार्यतः दिवाला निकाल देती हैं। भारत की औद्योगिक सहकारिताएँ भी इसका कोई विशेष अपवाद नहीं हैं। कारण सीधा-सादा है। पूँजीवादी 'साधन'

से आप सहकारी 'साध्य' की प्राप्ति नहीं कर सकते।

अपने उत्पादन की बिक्री-व्यवस्था करना औद्योगिक सहकारी समितियों के सामने आज एक भारी समस्या है। यहाँ तक कि वे सहकारिताएँ भी जो इन उत्पादक सहकारिताओं की वस्तुओं का उपयोग कर सकती हैं अपनी जरूरत की चीजें इनसे नहीं खरीदती। इस सम्बन्ध में सरकार मदद दे सकती है। वह अनेक समितियों, सङ्गठनों और स्थानीय विभागों को ऋण तथा उपदान देती है। इस प्रकार के ऋण और उपदान नकद रूप में न दे कर, नकद और जिन्स दोनों रूपों में दिये जाने चाहिये अर्थात् ऋण व उपदान का कुछ अंश औद्योगिक सहकारिताओं के उत्पादनों के रूप में दिया जा सकता है। इस प्रकार यह व्यवस्था उत्पादन करनेवाली तथा अन्य सहकारी समितियों को परस्पर जोड़ने के लिए एक उपयोगी कड़ी हो सकती है। स्वयम् सरकार को भी उनके उत्पादनों का व्यवहार करना चाहिये।

—सैम एम. नेकसतखान

किल्ले सोनगढ
जिला सूरत (गुजरात)

१३ अगस्त १९६४

महोदय,

खादी ग्रामोद्योग, वर्ष १०, अंक ११ में प्रकाशित "गोबर गैस सयंत्र विभिन्न उपयोग और समाज पर प्रभाव" लेख में लेखक श्री जशभाई झ पटेल ने विभिन्न जलावनो का कॅलरी मूल्य, उसकी योग्यता और प्रभावी मूल्य दर्शानेवाली तालिका दी है।

लेख के दूसरे पैरा में लेखक ने कहा है कि गैस का उष्मीय मान प्रति घनफुट ५५० ब्रिटिश थर्मल युनिट (ब्रि थ यु) है और इस गैस का २५० घनफुट ८२ पौण्ड जलावन लकड़ी का काम देता है। इस ओर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। लेख में बताये अनुसार २५० घनफुट गोबर गैस, जिसका कुल कॅलरी मूल्य 250×550 अर्थात् १,३७,५०० ब्रि थ यु होता है, ८२ पौण्ड जलावन लकड़ी के बराबर बताया गया है जबकि जलावन लकड़ी का नीचे दिये गये सगणन के अनुसार कॅलरी मूल्य ६,९८,२०० ब्रि थ यु होता है।

संगणना

२५० घनफुट गोबर गैस का प्रति
घनफुट ५५० ब्रि थ यु की दर से
कॅलरी मूल्य = १,३७,५०० ब्रि थ यु.
८२ पौण्ड जलावन लकड़ी का प्रति
पौण्ड २,१४० किलो कॅलरी की
दर से कॅलरी मूल्य = $\frac{८२ \times २,१४० \times १००}{२५२}$

(१ ब्रि थ यु = २५२ कॅलरी) = ६,९८,२०० ब्रि थ यु

टी कल्लपट्टी स्थित ग्रामीण विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र के कारखाना विभाग में प्रमुख शिक्षक ने लकड़ी जलावन का इस्तेमाल करनेवाले निर्धूम चूल्हों की, उष्मा ऊर्जा स्रोत के रूप में, योग्यता निश्चित करने के लिए विस्तृत प्रयोग किये हैं। उनसे यह पाया गया कि टी कल्लपट्टी में तैयार किये गये चूल्हों की योग्यता ३० से ३५ प्रति शत है, न कि १७ ३ प्रति शत जैसा कि लेख में बताया गया है। यदि यह भी मान ले कि चूल्हों की योग्यता लकड़ी जलावन का इस्तेमाल करते हुए १७ ३ प्रति शत है और गोबर गैस की ६० प्रति शत, तो वस्तुतः उपभोग की गयी उष्मा-ऊर्जा, एक ही किस्म का काम करने के लिए, गोबर गैस और लकड़ी जलावन के लिए क्रमशः $\frac{१,३७,५०० \times ६०}{१००}$ अर्थात्

१००

८२,५०० ब्रि थ यु और $\frac{६,९८,२०० \times १७}{१००}$ ३ अर्थात्

१,२०,७८८ ब्रि थ यु होगी।

लेखक महोदय अपने लेख में बताये निष्कर्ष पर किस प्रकार पहुँचे हैं, जबकि संगणना से कुछ और परिणाम निकलता है, इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

टी. कल्लपट्टी (मद्रास)

२१ अगस्त १९६४

—पी संजीव शेट्टी

—पी. एस. मंजनाथ

श्री जशभाई श पटेल लिखते हैं :

ईंधन के रूप में एक मन लकड़ी के स्थान पर २५० घनफुट गोबर गैस की सख्या हिसाब लगाकर नहीं प्राप्त की गयी है। यह संख्या वास्तविक व्यवहार से प्राप्त की गयी है। दत्तापुर स्थित गोबर गैस संयंत्र से १९६२-६३ के समूचे वर्ष में २,०३,३०० घनफुट गैस की प्राप्ति हुई और उसी वर्ष भोजन बनाने के लिए उक्त गैस ने ८०० मन (एक मन = ८२ पौण्ड) जलावन की लकड़ी का काम दिया। इस प्रकार प्रति एक मन लकड़ी के बराबर गोबर गैस की मात्रा $\frac{२,०३,३०० - ८००}{१३} = २५४$ घनफुट आती है।

धूमविहीन चूल्हों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ईंधन की लकड़ी के लिए जो २०-२५ प्रति शत क्षमता प्राप्त की है, वह सराहनीय है। मैंने अपने लेख में भोजन बनाने के लिए ईंधन के स्रोत के रूप में जलावन की लकड़ी की क्षमता १७ ३ प्रति शत बतायी है। यह प्रातिशत्य डॉमैस्टिक फ्यूएल्स इन इण्डिया से लिया गया है।

मेरे विचार से जलावन की लकड़ी की क्षमता के सम्बन्ध में यह कम सख्या वास्तविकता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करनेवाली प्रतीत होती है। यहाँ यह बताया जाना आवश्यक है कि भारत में सम्भवतः कुल परिवारों के एक प्रति शत के दसवें हिस्से से भी कम परिवार निर्धूम चूल्हों का उपयोग करते हैं।

यह भी स्पष्ट है कि लकड़ी जैसे जलावन की क्षमता का मामला वास्तविक व्यवहार में बड़ा 'अनिश्चित' है। सम्भवता परीक्षण के लिए अपनाये गये तरीके सदैव ही उन अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिनके अन्तर्गत पारिवारिक भोजनालयों में ईंधन की लकड़ी का उपयोग होता है। यह भी सम्भव है कि दत्तापुर में भोजन बनाने के लिए भट्टियों जैसा विशेष प्रबन्ध होने की वजह से गोबर गैस का अधिक कुशलता के साथ व्यवहार किया जा रहा हो।

पृष्ठ ७२२ पर एक भूल है। उक्त पृष्ठ पर गोबर गैस की लपट का तापमान १००००° फर्नहाइट बताया गया है। सही तापमान १०००° फर्नहाइट है।

बम्बई २८ अगस्त १९६४

[श्री पटेल ने ऊपर जिस भूल का जिक्र किया है वह हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजे गये उनके लेख की मूल प्रति में ही थी। तथापि, पाठकों को इस कारण जो असुविधा हुई, उसका हमें खेद है। —सम्पादक]

सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और प्रामोद्योग कमीशन के लिए 'प्रामोद्य' इला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५९ से प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल : एसोसियेटेड एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ५०५ तारदेव, आर्थर रोड, बम्बई-२४। वार्षिक झूल्का : ₹ ५० रुपये, एक प्रति : २५ पैसे।

रविवी ग्रामिण

ग्रामीण जीवन, समाज और अर्थशास्त्र विषयक मासिक

वर्ष : १० : अंक : १-१२

अक्टूबर १९६३-सितम्बर १९६४

विषय सूची

सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार



कामये बुद्धिमान्नाम्।
प्राणिनाम् अतिनिशानम्॥

प्रचार निदेशालय

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन

आमोदय, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम)

बम्बई-५६

लेखों की सूची

	माह	पृष्ठ
अखाद्य तेल से विकेंद्रित साबुन उत्पादन —सुभाष चन्द्र सरकार	सितम्बर १९६४	८२६-८३०
अन्नोपभोग और घटिया से बढ़िया अनाज की ओर एक अध्ययन —तण्डलम सो यशवत और रा राजगोपालन	जून १९६४	६२३-६३०
अभिनव भेड-पालन —गुलजार सिंह	जून १९६४	६४२-६४३
अम्बर की शक्यता —शकरलाल बैकर	अक्तूबर १९६३	५६-६०
अहमदनगर जिले में गाँवों का आर्थिक सर्वेक्षण और आयोजन —मधुसूदन द साठे	अगस्त १९६४	७२७-७३६
अहिंसा के सामाजिक निहितार्थ —उछरगाराय न डेवर	फरवरी १९६४	३३६-३४५
आर्थिक प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था —मुहम्मद मोहसीन	सितम्बर १९६४	७८५-७८९
आर्थिक विकास का साधन : शिक्षा —म बालसुब्रह्मण्यम्	नवम्बर १९६३	१७१-१७४
आर्थिक विकास पर प्रधान मंत्री के विचार —वैकुण्ठ ल मेहता	अगस्त १९६४	७१९-७२१
आदिवासियों के लिए न्यूनतम जीवन-स्तर —दत्तात्रेय ना वान्देकर	जनवरी १९६४	३००-३०२
आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामोद्योग —बहराम होरमसजी मेहता	अक्तूबर १९६३	९०-९३
आन्ध्र प्रदेश की दस्तकारियों —श्रीपति रगनाथ	अप्रैल १९६४	५०७-५०९
आधुनिक मधुमक्खी-पालन —जे राजग्या	मार्च १९६४	४२९-४३१
आय वितरण पर एक दृष्टि —विद्या सागर महाजन	जनवरी १९६४	२९२-२९९
आयोजन का गांधीवादी दृष्टिकोण —वैकुण्ठ ल मेहता	अक्तूबर १९६३	११-१५
इजरायल में कृषि-उद्योग समन्वय —वैकुण्ठ ल मेहता	सितम्बर १९६४	७७५-७७७

लेखों की सूची

	माह	पृष्ठ
ईंट और चूना उद्योग का एक अध्ययन —वे आ वासुदेवराजू	दिसम्बर १९६३	२६०-२६२
उड़ीसा की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और खादी तथा ग्रामोद्योग —वेदनभट्टल सीतारामय्या	नवम्बर १९६३	१७७-१८३
उत्तर प्रदेश में गुड़ की सहकारी विक्रय व्यवस्था —भारत भूषण कसाल	मई १९६४	५३१-५३६
उत्तर प्रदेश में गुड़ के संग्रह की समस्याएँ —भारत भूषण कसाल	सितम्बर १९६४	७९९-८०१
उन्नत धान-कुटाई चक्की —रा कृ श्रीवास्तव, एस वाय नन्दनवार और भा य राव	अगस्त १९६४	७२६
उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन और ग्राम इकाई —प्रमोद कुमार पटनायक	अप्रैल १९६४	४९४-४९८
ऊनी और पशम वस्त्रों में सुधार के लिए भेड़-पालन —पेकल श्रीरामलू पैट्रो	जुलाई १९६४	६७९-६८३
एक राजस्थानी गाँव में कुम्भकारी उद्योग —खेमराज पिछोलिया	जून १९६४	६४१-६४२
औद्योगिक सहकारिताएँ और लोकतांत्रिक समाजवाद —त्रिलोक नाथ भास्कर	अगस्त १९६४	७४८-७५१
औद्योगिक सहकारी समितियाँ —मसूद अली मिर्जा	अप्रैल १९६४	५०२-५०४
कछार का सामाजार्थिक सर्वेक्षण —सुहास चटर्जी	सितम्बर १९६४	७८२-७८४
कश्मीरी 'गब्बे' की कहानी —इन्दर मो भटनागर	जून १९६४	६४३-६४४
कागज की पारिभाषिक स्थिरता —ग ह गोधलेकर	जुलाई १९६४	६५४-६५७
किसानों के लिए उर्वरक —मगुदेसन बालसुब्रह्मण्यन	अगस्त १९६४	७२४-७२५
कृषिक अनुसंधान और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था —अब्दुर रहीम खॉ	अक्तूबर १९६३	९४-९६
कृषि में निम्बौरी के गूदे और खली का उपयोग —अपर्णा सजीव सिरूर	अगस्त १९६४	७६०-७६१
केरल में सहकार और कृषि उत्पादन —कृ श्रीकण्ठन नायर	जून १९६४	६०३-६०७
खादी आन्दोलन का नया अध्याय (सम्पादकीय)	अप्रैल १९६४	४५९-४६२
खादी आन्दोलन का बुनियादी विचार —कमलेश्वरानन्द पाण्डेय	मार्च १९६४	४३२-४३४

—शकरलाल बैकर	अप्रैल १९६४	४९०-४९३
खादी और अर्थ-व्यवस्था		
—वैकुण्ठ ल मेहता	फरवरी १९६४	३४६-३४९
खादी और औद्योगिक कानून		
—छीतरमल गोयल	अगस्त १९६४	७५८-७६०
खादी और ग्रामोद्योगों की प्रासंगिकता		
—वैकुण्ठ ल मेहता	जनवरी १९६४	२७६-२७९
खादी और ग्रामोद्योगों के लिए संगठनात्मक स्वरूप		
—अक्षय कुमार करण	सितम्बर १९६४	७७८-७८१
खादी का भविष्य		
—रामकृष्णराव कृ पाटिल	अक्तूबर १९६३	४३-४७
खादी का मिशन		
—झवेरभाई पटेल	अक्तूबर १९६३	४८-५५
खादी कार्यक्रम और उसकी आलोचना		
—वैकुण्ठ ल मेहता	अप्रैल १९६४	४६७-४७२
खादी किस ओर ?		
—ध्वजा प्रसाद साहू	अक्तूबर १९६३	४१-४२
खादी-ग्रामोद्योग और प्रचार कार्य		
—सुभाष चन्द्र सरकार	दिसम्बर १९६३	२११-२१७
खादी-ग्रामोद्योग तथा उनकी स्फीति निष्पन्न क्षमता		
—सोमनाथन् नायर	फरवरी १९६४	३६५-३७२
खादी व ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में सहकार : समस्या का मूल		
—उछरगराय न डेबर	जनवरी १९६४	२७३-२७५
गत पन्द्रह वर्ष में रोजगारी व बेरोजगारी		
—भगवन्त नागेश दातार	अक्तूबर १९६३	७०-७५
गरीब देश, आर्थिक विकास और समाज कल्याण		
—ने सु तिरुवेकटाचारी	मई १९६४	५७४-५७६
गांधी सेवक समाज		
—वैकुण्ठ ल मेहता	मार्च १९६४	४५४-४५६
गाँव और शहर		
—वैकुण्ठ ल मेहता	जून १९६४	५९९-६०२
गोबो के लिए ऋण की व्यवस्था		
—ब्रह्मदेव मुकुर्जी	अक्तूबर १९६३	२९-३५

	माह	पृष्ठ
ग्राम और लघु उद्योगों के लिए संगठन —ललित कुमार मित्र	नवम्बर १९६३	१४६-१५१
ग्राम पचायतों को प्राणवान बनाने का कार्यक्रम —रोम दास	दिसम्बर १९६३	२२९-२३२
ग्राम सफाई —जागेश्वर गोपाल श्रीखण्डे	फरवरी १९६४	३८७-३८८
ग्राम्य उद्योगों के विकास के लिए आयोजन —मरियप्पन प गुरुसामी	अगस्त १९६४	७३७-७४१
ग्राम्य जीवन में स्थिरता और परिवर्तन —सुभाष चन्द्र सरकार	जनवरी १९६४	३१९-३२५
ग्राम्य विकास —उछरगाराय न डेबर	अगस्त १९६४	७११-७१८
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और ग्राम का आकार —जुगताराम दवे	नवम्बर १९६३	१९१-१९४
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और ग्राम का आकार —रत्तिमाई गोधिया	नवम्बर १९६३	१९४-१९८
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और महिलाएँ —सत्या कुमारी	मई १९६४	६७६-५७९
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के चन्द पहलू —मोरारजी देसाई	अक्तूबर १९६३	१६-१९
ग्रामीण उद्योग और लोकतांत्रिक समाजवाद —वे पद्मनाभन	सितम्बर १९६४	७९०-७९३
ग्रामीण औद्योगीकरण —पुतुपरम्बिल म मथाई	अप्रैल १९६४	४८१-४८४
ग्रामीण औद्योगीकरण और भूमि-सुधार —वे आ वासुदेवराज	अगस्त १९६४	७५२-७५५
ग्रामीण औद्योगीकरण के लाभ —भारत भूषण कसाल	फरवरी १९६४	३५४-३५८
ग्रामीण औद्योगीकरण से वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं की भूमिका —मजेश्वर सदाशिव राव	अक्तूबर १९६३	१११-११६
ग्रामीण औद्योगीकरण में समस्याएँ —वैकुण्ठ ल मेहता	मई १९६४	५१९-५२३
ग्रामीण कुम्हारी उद्योग में चीनी मिट्टी के बर्तन —श्री कृ मिर्मिरा	दिसम्बर १९६३	२४७-२४८
ग्रामीण रोजगारी और योजना —चित्तप्रिय मुखर्जी	अक्तूबर १९६३	१००-११०

	माह	पृष्ठ
ग्रामीण महाराष्ट्र में सहकार की प्रगति —प्रभाकर नाडकर्णी	मार्च १९६४	४४१-४४८
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग कार्यक्रम —त्रिभुवन नारायण सिंह	अक्टूबर १९६३	२६-२८
ग्रामीण क्षेत्रों में गैस संयंत्र —दत्तात्रेय ना वान्देकर	अप्रैल १९६४	४९९-५०१
ग्रामोद्योगीकरण का बिक्री विषयक पहलू —श्रीपति रगनाथ	नवम्बर १९६३	१९९-२०१
ग्रामोद्योगों के लिए मध्यम प्रौद्योगिकी —त्रिभुवन नारायण सिंह	अप्रैल १९६४	४७३-४७७
गुजरात के तीन गांवों में ग्राम-नेतृत्व —यशवन्तसिंह जाडेजा	जून १९६४	६१४-६२०
गुजरात में रोजगारी की स्थिति : १९५१-६१ —रामदास किशोरदास अमीन	दिसम्बर १९६३	२२४-२२८
गुड और खाण्डसारी उद्योग —दीना नाथ दुबे	फरवरी १९६४	३८९-३९०
गोबर गैस संयंत्र . एक अध्ययन —जशभाई झ पटेल	सितम्बर १९६४	७९७-७९९
गोबर गैस संयंत्र : एक अध्ययन —एस डी तेजनारायण और राम मूर्ति	जुलाई १९६४	६९९-७०१
गोबर गैस संयंत्र : विभिन्न उपयोग और समाज पर प्रभाव —जशभाई झ पटेल	अगस्त १९६४	७२२-७२३
चीनी का स्रोत : ताड़ —प्रकाश चन्द्र वासनीय	मई १९६४	५५३-५५८
जम्मू और कश्मीर का पशुधन : चन्द समस्याएँ —माखन लाल भट	सितम्बर १९६४	८०२-८०९
जम्मू और कश्मीर में रेशम उत्पादन का विकास —माखन लाल भट	जुलाई १९६४	६६९-६७८
जवाहरलाल नेहरू —वैकुण्ठ ल मेहता	जून १९६४	अतिरिक्त पृष्ठ
जवाहरलाल नेहरू —सुभाष चन्द्र सरकार	जून १९६४	अतिरिक्त पृष्ठ
तृतीय पंच वर्षीय योजना में रेशम खादी उद्योग —सत्य रजन सेन	नवम्बर १९६३	१८४-१८६
तेल उत्पादक सहकारों को सुझाव —त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्ति	जून १९६४	६३७-६४०

	माह	पृष्ठ
तेल पेराई में सुधार —त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्ति	मार्च १९६४	४४९-४५३
दरिद्रता का अभिशाप —विवेकानन्द	जनवरी १९६४	२६९-२७२
दशम वर्ष (सम्पादकीय)	अक्तूबर १९६३	१-८
दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा —लालभाई र देसाई	अप्रैल १९६४	४८५-४८९
दक्षिण कॅनरा में बदलौन व्यापार —नवीनचन्द्र कृ तिगलाया	मिातम्बर १९६४	८१३-८१५
दक्षिणी राज्यों में कृषि श्रमिक —कृ श्रीकण्ठन नायर	दिसम्बर १९६३	२४९-२५३
धान की हाथ कुटाई व सेलीकरण —तो मी सुन्दरम	मई १९६४	५७९-५८०
नीरा बनाम ताडी —वैकुण्ठ ल मेहता	जुलाई १९६४	६४७-६४९
नेपाल की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था —यादव प्रसाद पन्त	नवम्बर १९६३	१५२-१५७
पचायत राज —पुरुषोत्तम प्रभाकर	मई १९६४	५५९-५६२
पचायत राज और सामुदायिक विकास —नफीस बेग	फरवरी १९६४	३६२-३६४
पचायत राज के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन —हबीबुर रहमान	जुलाई १९६४	६६०-६६२
पचायतो के साधन-स्रोत (पचायत राज सस्थाओं के वित्तीय साधन-स्रोतों का अध्ययन करनेवाले दल के प्रतिवेदन से)	फरवरी १९६४	३८५-३८६
पंजाब की अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ —विक्टर सा डी'सोजा	मार्च १९६४	८०८-४१६
परिगणित जातियों तथा जन-जातियों के लिए रोजगारी —उछरगाराय न देबर	अप्रैल १९६४	८६३-८६६
परिगणित जातियों व परिगणित जन-जातियों की अवस्था से सुधार —वैकुण्ठ ल मेहता	मार्च १९६४	३९८-४००
पश्चिम बंगाल के कुटीर शिल्प —आशीश कुमार बसु	फरवरी १९६४	३७३-३७४
प्रचार की निरर्थकता —सुभाष चन्द्र सरकार	जुलाई १९६४	७०२-७०५

	माह	पृष्ठ
पाली में एकमुश्त कार्यक्रम —माखन लाल भट	जनवरी १९६४	३०७-३१३
पूर्वी उत्तर प्रदेश की अविकसित अर्थ-व्यवस्था —इस्तीफा हुसैन	मार्च १९६४	४३५-४४०
बंगाल में शहरीकरण के कुछ पहलू —मीरा गुहा	अक्तूबर १९६३	१२५-१३०
बढते मूल्य —उछरगराय न डेबर	सितम्बर १९६४	७७१-७७४
बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में वानस्पतिक सम्पत्ति —सुधाशु कुमार जैन	मई १९६४	५४१-५४५
बिहार में आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और रोजगारी —शैलेश कुमार बोस	नवम्बर १९६३	१६१-१७०
बुनाई उपदान योजना के निहितार्थ —वैकुण्ठ ल मेहता	दिसम्बर १९६३	२०७-२१०
बुनाई सहायता का प्रस्ताव (सम्पादकीय)	नवम्बर १९६३	१४३-१४५
बैलों की आत्मा का निर्यात व्यापार —पोन्नूसामी कुप्पु राव	मई १९६४	५६३-५६४
भ्रष्टाचार निवारण के लिए उपाय (सन्तानम् समिति के प्रतिवेदन से)	सितम्बर १९६४	८१६-८२५
भारत की अर्थ-व्यवस्था में भविष्यो का स्थान —सुशील चन्द्र चौधरी और रघुनाथ गिरी	जनवरी १९६४	२८०-२९१
भारत पर नयी दृष्टि —गौरी शंकर रायचौधरी	अक्तूबर १९६३	११७-११९
भारत में तिलहन पेरवाई उद्योग —तरलोचन सिंह	मई १९६४	५७०-५७३
भारत में पूँजी संचयन और निवेश —अमृतलाल दत्त	अक्तूबर १९६३	७६-८९
भारत में मधुमक्खी-पालन —क्लाँड आर केलॉग	जुलाई १९६४	६५८-६५९
भारत में मधुमक्खी-पालन —सुभाष चन्द्र सरकार	मार्च १९६४	४१७-४२०
भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का स्वरूप —उछरगराय न डेबर	अक्तूबर १९६३	५-१०
भारतीय आहार, औद्योगिकी और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था —सुनील कुमार मुखर्जी	नवम्बर १९६३	१५८-१६०

लेखों की सूची

ज

	माह	पृष्ठ
भारतीय निर्यात व्यापार तीव्र विस्तार की आवश्यकता —युवेश चन्द्र शर्मा	अगस्त १९६४	७६२-७६५
मद्रास के एक गाँव का आर्थिक चित्र —त सो यशवत और ने सु तिरुवेकटाचरी	सितम्बर १९६४	८१०-८१२
मधुमक्खियों और परागाधान —हरिहरन विश्वनाथन	मार्च १९६४	४२६-४२८
मधुमक्खी-पालन उद्योग की समस्याएँ —राम सुभग सिंह	मार्च १९६४	४०४-४०७
मधुमक्खी-पालन उद्योग समीक्षा —सीताराम ग शेट्टे	मार्च १९६४	४२१-४२२
मिट्टी की अभिव्यक्ति और अपारदर्शी काचनः चन्द प्रयोग —जागेश्वर गो श्रीखण्डे और यशवत वि खेर	जून १९६४	६२१-६२२
मितव्ययी तिलहन एकत्रण की ओर —पु वि श्रीकण्ठ राव	अक्तूबर १९६३	१३१-१३४
मुर्शिदाबाद का सूती और रेशमी खादी उद्योग —कमल बनर्जी	अगस्त १९६४	७४२-७४५
मुर्शिदाबाद का हाथी दात शिल्प —कमल बनर्जी	मई १९६४	५६५-५६९
मैसूर के गाँवों में प्रचलित क.स-बंध —वन्दार वेकप्प शेट्टी	फरवरी १९६४	३५९-३६१
मैसूर के दो गाँवों में कर्जदारी —वन्दार वेकप्प शेट्टी	जुलाई १९६४	६६३-६६८
मैसूर में ग्राम्य जन-शक्ति परियोजनाएँ —स म वीरराघवाचार	मई १९६४	५३७-५४०
मौन-पालन में अनुसंधान —गोविन्द बालकृष्ण देवडीकर	मार्च १९६४	४२३-४२५
मथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक —जोसेफ दु मुन्दरम्	अक्तूबर १९६३	६१-६९
युगोस्लाविया में कृषि —मिलम आयवनोविक	जुलाई १९६४	६५०-६५३
राष्ट्रीय आर्थिक आयोजन पर विचार —शचीन्द्रलाल घोष	दिसम्बर १९६३	२४३-२४६
राष्ट्रीय एकता का आर्थिक पक्ष —जवाहरलाल नेहरू	फरवरी १९६४	३३३-३३५
रेशम उद्योग व रेशम अनुसंधान —कमल बनर्जी	जनवरी १९६४	३१४-३१६

	माह	पृष्ठ
रेशम कीट-पालन. समस्याएँ और सम्भाव्यताएँ (श्री सत्य रजन मेन द्वारा प्रस्तुत 'नोट' पर आधारित)	दिसम्बर १९६३	२३३-२४२
रेखा उद्योग का विकास —सजीवराव कृ कल्लापुर	नवम्बर १९६३	१८७-१९०
लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी —दया कृष्ण मल्होत्रा	अप्रैल १९६४	४७८-४८०
लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों का सामान्य प्रबन्ध —पे बाल कृष्ण मूर्ति	अगस्त १९६४	७५६-७५८
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण —चित्तूर। बेकट राघवुलू	जून १९६४	६०८-६१३
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सहकारिता प्रज्ञासन (बेङ्गलूर मेहता समिति के प्रतिवेदन से)	जुलाई १९६४	६९०-६९६
वर्धा घाटी से तेल सम्प्राप्ति —राम कृ श्रीवास्तव और माधव रा देशपाण्डे	मई १९६४	५२४-५२६
वस्त्र छपाई —दनकुमार पै	अगस्त १९६४	७४६-७४७
वस्त्र रंगाई के सिद्धान्त —पेराल श्रीरामलू पैट्रो	दिसम्बर १९६३	२५४-२५९
बालोद महाल विकास योजना : एक विवेचन —विमल शाह	जनवरी १९६४	३०३-३०५
विकेन्द्रित अर्थ-रचना —देवेन्द्र कुमार गुप्त	नवम्बर १९६३	१७५-१७६
विकेन्द्रित कताई और ग्रामीण रोजगारी —केशव ग देवधर और सौमित्र दे नाडकणो	मई १९६४	५२७-५३०
विभिन्न ग्रामोद्योगों का सापेक्षिक महत्व —देवेन्द्र कुमार गुप्त	सितम्बर १९६४	७९४-७९५
विस्तार पद्धतियों का प्रयोग —सोमसुन्दरम् शनमुगम्	जुलाई १९६४	६९७-६९८
शैक्षणिक प्रगति तथा औद्योगीकरण —कन्दस्वामी अरुणचालम्	अक्तूबर १९६३	२०-२५
समग्र विकास कार्यक्रम —कोदण्डरामन वैद्यनाथन	अप्रैल १९६४	५०५-५०६
समृद्धि की दुविधा —सुभाष चन्द्र सरकार	अक्तूबर १९६३	१३५-१३७

	माह	पृष्ठ
सहकार पर वैकुण्ठभाई के विचार —रतिलाल महेता	जुलाई १९६४	७०६-७०८
सहकारी प्रशासन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —एन वाय खेर	मिम्बर १९६४	७९६-७९७
श्री-शिक्षा की समस्याएँ —श्रीपति श्रीदेवी	अक्तूबर १९६३	१२०-१२४
स्कूली बच्चों के विकास पर ताड़-गुड का प्रभाव —मेरी जार्ज	जुलाई १९६४	६८४-६८९
सामाजिक अनुसंधान की भूमिका —सोमसुन्दर यशवन्त	जनवरी १९६४	३१७-३१८
सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर (ढेबर कमेटी का प्रतिवेदन)	जून १९६४	५८३-५९८
सामान्य उत्पादन कार्यक्रम —उछरगराय न ढेबर	मार्च १९६४	३९५-३९७
सूक्ष्म प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान —भारतानन्द	मई १९६४	५४६-५५२
सोवियत संघ में मधुमक्खी-पालन —सीताराम शेण्डे	दिसम्बर १९६३	२१८-२२३
हमारी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर खादी का प्रभाव —अरुण चन्द्र गुहा	अक्तूबर १९६३	३६-४०
हमारे हड्डी स्रोत —शिशिर कुमार बराट	जानुवरी १९६३	९७-९९
हरसूद सामुदायिक विकास खण्ड का सर्वेक्षण और आयोजन (विस्तार अधिकारियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण पर आधारित)	जून १९६४	६३१-६३६
हाथ कागज उद्योग में निस्पन्दक पत्र का उत्पादन —म सदाशिव राव और बालचन्द्र मा अग्नीकर	फरवरी १९६४	३५०-३५३
त्रिपुरा की अर्थ-व्यवस्था और खादी-ग्रामोद्योगों की सम्भावना	अप्रैल १९६४	५१०-५१२
सम्पादकीय		
खादी आन्दोलन का नया अध्याय	अप्रैल १९६४	४५९-४६२
दशम वर्ष	अक्तूबर १९६३	१-४
बुनाई सहायता का प्रस्ताव	नवम्बर १९६३	१४३-१४५

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम	माह	पृष्ठ
आदिवासी	प्रकाशक-आदिवासी अनुसंधान केन्द्र, उड़ीसा	अप्रैल १९६४ ५१६
इकनॉमिक अफेयर्स	सम्पादक-हिमासर राय	अक्तूबर १९६३ १३९-१४०
इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेण्ट प्रोग्राम इन इण्डिया	प्रकाशक-सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय नयी दिल्ली।	नवम्बर १९६३ २०४
इवोल्यूशन ऑफ पचायती राज एक्शन रिसर्च एण्ड इट्स इम्पॉर्टेन्स इन एन अण्डरडेवलपड इकनॉमी	लेखक-आर वी जठार	सितम्बर १९६४ ८३२-८३३
एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड इकनॉमिक डेवलपमेण्ट इन इण्डिया	प्रकाशक-प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इन्स्टीट्यूट, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	अक्तूबर १९६३ १३९
एस्पेक्ट्स ऑफ इकनॉमिक चेन्ज एण्ड पॉलिसी इन इण्डिया : १८००-१९६०	सम्पादक-राल्फ ब्रेबाण्टी और जोसेफ जे स्पेगलर	जनवरी १९६४ ३२६-३२९
कोऑपरेटिव पालिसी एण्ड प्रोग्रैम्स	लेखक-वी वी भट्ट	अक्तूबर १९६३ १३८-१३९
कोऑपरेशन अंज ए रेमेडी फॉर रूरल पावर्टी	प्रकाशक-नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया, नयी दिल्ली।	अक्तूबर १९६३ १४०
दि ट्रायबल ब्लड ऑफ बेरियर एल्विन : ऐन ऑटोबायोग्राफी	लेखक-एम नुरुल हक	अक्तूबर १९६३ १४०
दि प्रमोशन ऑफ इम्प्लायमेंट इन रूरल एरियाज इन इण्डिया	प्रकाशक-ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई।	सितम्बर १९६४ ८३१-८३२
रूरल इण्डस्ट्रीयलाइजेशन व्यापार सम्बन्धी व्याख्यान	प्रकाशक-इण्टरनेशनल लेबर ऑफिस, नयी दिल्ली।	अगस्त १९६४ ७६७-७६८
स्टडीज इन इण्डियन फॉकलोर	लेखक-वी ए वासुदेवराजू	अप्रैल १९६४ ५१५
हिन्दूज ऑफ दि हिमालयाज हैडबुक ऑफ कॉमर्सियल इन्फारमेशन	प्रकाशक-गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पूना।	अप्रैल १९६४ ५१३-५१५
	सम्पादक-शकर सेन गुप्त और के डी उपाध्याय	अगस्त १९६४ ७६६-७६७
	लेखक-नोराल्ड डी बेर्रेमन	दिसम्बर १९६३ २६३-२६५
	प्रकाशक-वाणिज्य, अनुसंधान तथा सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार, कलकत्ता	अप्रैल १९६४ ५१५-५१६

	माह	पृष्ठ
टीका-टिप्पणी		
उत्तर प्रदेश में गुड़ के संग्रह की समस्याएँ —भारत भूषण कसाल	सितम्बर १९६४	७९९-८०१
गोबर गैस संयंत्र एक अध्ययन —जशभाई झ पटेल	सितम्बर १९६४	७९७-७९९
भारत में मधुमक्खी-पालन —क्लॉड आर केलॉग	जुलाई १९६४	६५८-६५९
विचार-विमर्श —सत्य रजन सेन	जनवरी १९६४	३०६
सहकारी प्रशासन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —एन वाय खेर	सितम्बर १९६४	७९६-७९७
पाठको के विचार		
(जशभाई पटेल)	नवम्बर १९६३	२०२-२०३
(नागेश्वर प्रसाद)	नवम्बर १९६३	२०३
(मनुभाई शाह)	दिसम्बर १९६३	२६६
(प्रो डब्ल्यू एफ वर्थिम)	जनवरी १९६४	३३०
(एस आर दास)	फरवरी १९६४	३९१
(के एल राव)	फरवरी १९६४	३९१-३९२
(दत्तात्रेय गोपाल कर्वे)	फरवरी १९६४	३९२
(सैम एस नेकसतखान)	सितम्बर १९६४	८३४-८३५
(पी सजीव शेट्टी)	सितम्बर १९६४	८३५-८३६
(पी एस मजनाथ)	सितम्बर १९६४	८३५-८३६
(जशभाई झ पटेल)	सितम्बर १९६४	८३६

लेखक और उनकी रचनाएँ

अग्नीकर, बालचन्द्र भातों		
हाथ कागज उद्योग में निर्यदक पत्र का उत्पादन (म. सदाशिव राव के सहयोग से)	फरवरी १९६४	३५०-३५३
अमीन, रामदास किशोरदास		
गुजरात में रोजगारी की स्थिति १९५१-६१	दिसम्बर १९६३	२२४-२२८
अरुणाचलम्, कन्दस्वामी		
शैक्षणिक प्रगति तथा औद्योगीकरण	अक्तूबर १९६३	२०-२५
आयचनोचिक, मिलम		
युगोस्लाविया में कृषि	जुलाई १९६४	६५०-६५३

	माह	पृष्ठ
कसाल, भारत भूषण		
उत्तर प्रदेश में गुड की सहकारी विप्रेय व्यवस्था	मई १९६४	५३१-५३६
उत्तर प्रदेश में गुड के सग्रह की समस्याएँ	मितम्बर १९६४	७९९-८०१
ग्रामीण औद्योगीकरण के लाभ	फरवरी १९६४	३५४-३५८
करण, अक्षय कुमार		
खादी और ग्रामोद्योगों के लिए सगठनात्मक स्वरूप	मितम्बर १९६४	७७८-७८१
कल्लापुर, संजीवराव कृष्णराव		
रेशा उद्योग का विकास	नवम्बर १९६३	१८७-१९०
कुमारी, सत्या		
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और महिलाएँ	मई १९६४	५७६-५७९
कृष्णमूर्ति, त्यमगुण्डलू		
तेल उत्पादक सहकारी को मुझाव	जून १९६४	६३७-६४०
तेल पेटाई में सुधार	मार्च १९६४	४४९-४५३
केलॉग, क्लॉड आर.		
भारत में मधुमक्खी-पालन	जुलाई १९६४	६५८-६५९
खॉ, अब्दुर रहीम		
कृषिक अनुसधान और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	अक्तूबर १९६३	९४-९६
खेर, एन वाय.		
सहकारी प्रशासन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	मितम्बर १९६४	७९६-७९७
खेर, यशवत विट्ठल		
मिट्टी की अभिषट्यता और अपारदर्शी काचन चन्द प्रयोग (जागेइवर गो श्रीखण्डे के सहयोग से)	जन १९६४	६२१-६२२
मिरी, रघुनाथ		
भारत की अर्थ-व्यवस्था में मवेशियों का स्थान (सुशील चन्द्र चौधरी के सहयोग से)	जनवरी १९६४	२८०-२९१
गुप्त, देवेन्द्र कुमार		
विकेन्द्रित अर्थ-रचना	नवम्बर १९६३	१७५-१७६
विभिन्न ग्रामोद्योगों का सापेक्षिक महत्व	मितम्बर १९६४	७९४-७९५
गुरुसामी, भरियप्पन परयपट्टी		
ग्राम्य उद्योगों के विकास के लिए आयोजन	अगस्त १९६४	७३७-७४१
गुहा, अरुण चन्द्र		
हमारी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर खादी का प्रभाव	अक्तूबर १९६३	३६-४०
गुहा, मीरा		
बगाल में शहरीकरण के कुछ पहलू	अक्तूबर १९६३	१२५-१३०
गोंधलेकर, गजानन हरि		
कागज की पारिमापिक स्थिरता	जुलाई १९६४	६५४-६५७

	माह	पृष्ठ
गोधिया, रतिभाई		
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और ग्राम का आकार	नवम्बर १९६३	१९४-१९८
गोयल, छीतरमल		
खादी और औद्योगिक कानून	अगस्त १९६४	७५८-७६०
घोष, शचीन्द्रलाल		
राष्ट्रीय आर्थिक आयोजन पर विचार	दिसम्बर १९६३	२४३-२४६
चटर्जी, सुहास		
कछार का सामाजिक सर्वेक्षण	सितम्बर १९६४	७८२-७८४
चौधरी, सुशील चन्द्र		
भारत की अर्थ-व्यवस्था में मवेशियों का स्थान (रघुनाथ गिरी के सहयोग से)	जनवरी १९६४	२८०-२९१
जार्ज, मेरी		
स्कूली बच्चों के विकास पर ताड़-गुड़ का प्रभाव	जुलाई १९६४	६८४-६८९
जाडेजा, यशवन्तसिंह		
गुजरात के तीन गाँवों में ग्राम-नेतृत्व	जून १९६४	६१४-६२०
जैन, सुधाशु कुमार		
बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में वानस्पतिक सम्पत्ति	मई १९६४	५४१-५४५
डी'सोजा, विक्टर सालवादोर		
पंजाब की अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ	मार्च १९६४	४०८-४१६
ढेबर, उछरंगराय नवलशकर		
अहिंसा के सामाजिक निहितार्थ	फरवरी १९६४	३३६-३४५
खादी व ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में सहकार . समस्या का मूल	जनवरी १९६४	२७३-२७५
ग्राम्य विकास	अगस्त १९६४	७११-७१८
परिगणित जातियों तथा जन-जातियों के लिए रोजगारी	अप्रैल १९६४	४६३-४६६
बढ़ते मूल्य	सितम्बर १९६४	७७१-७७४
भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का स्वरूप	अक्तूबर १९६३	५-१०
सामान्य उत्पादन कार्यक्रम	मार्च १९६४	३९५-३९७
तिगलाया, नवीनचन्द्र कृष्णप्पा		
दक्षिण कन्नरा में बदलौन व्यापार	सितम्बर १९६४	८१३-८१५
तिखवेकटाचारी, नेडूमरम सुन्दरराजअय्यंगर		
गरीब देश, आर्थिक विकास और समाज कल्याण	मई १९६४	५७४-५७६
मद्रास के एक गाँव का आर्थिक चित्र (त मो यशवत के सहयोग से)	सितम्बर १९६४	८१०-८१२
तेजनारायण, एस. डी.		
गोबर गैस सयत्र एक अध्ययन (राम मूर्ति के सहयोग से)	जुलाई १९६४	६९९-७०१

	माह	पृष्ठ
दत्त, अमृतलाल भारत में पूँजी संचयन और निवेश	अक्तूबर १९६३	७६-८९
दवे, जुगताराम ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और ग्राम का आकार	नवम्बर १९६३	१९१-१९४
दातार, भगवन्त नागेश गत पन्द्रह वर्ष में रोजगारी व बेरोजगारी	अक्तूबर १९६३	७०-७५
दास, राम ग्राम पंचायतो को प्राणवान बनाने का कार्यक्रम	दिसम्बर १९६३	२२९-२३२
दुबे, दीना नाथ गुड और खाण्डमारी उद्योग	फरवरी १९६४	३८९-३९०
देवडीकर, गोविन्द बालकृष्ण मौन-पालन में अनुसंधान	मार्च १९६४	४२३-४२५
देवधर, केशव गणेश विकेन्द्रित कताई और ग्रामीण रोजगारी (सौमित्र दे० नाडकर्णी के सहयोग से)	मई १९६४	५२७-५३०
देशपाण्डे, माधव राजाराम वर्धा घानी से तेल सम्प्राप्ति (राम कृ० श्रीवास्तव के सहयोग से)	मई १९६४	५२४-५२६
देसाई, मोरारजी रणछोडजी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के चन्द पहलू	अक्तूबर १९६३	१६-१९
देसाई, लालभाई रतनजी दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा	अप्रैल १९६४	४८५-४८९
नन्दनवार, एस. घाय उन्नत धान कुटाई चक्की (रा. कृ. श्रीवास्तव और भा. य. राव के सहयोग से)	अगस्त १९६४	७२६
नाडकर्णी, प्रभाकर शंकर ग्रामीण महाराष्ट्र में सहकार की प्रगति	मार्च १९६४	४४१-४४८
नाडकर्णी, सौमित्र देवीदास विकेन्द्रित कताई और ग्रामीण रोजगारी (केशव ग. देवधर के सहयोग से)	मई १९६४	५२७-५३०
नायर, कृष्णन श्रीकण्ठन् केरल में सहकार और कृषि उत्पादन दक्षिणी राज्यों में कृषि श्रमिक	जून १९६४ दिसम्बर १९६३	६०३-६०७ २४९-२५३
नायर, चम्पकमडम परमेश्वरन पिलै सोमनाथन खादी-ग्रामोद्योग तथा उनकी स्फीति निवारक क्षमता	फरवरी १९६४	३६५-३७२
नेहरू, जवाहरलाल राष्ट्रीय एकता का आर्थिक पक्ष	फरवरी १९६४	३३३-३३५
पटनायक, प्रमोद कुमार उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन और ग्राम इकाई	अप्रैल १९६४	४९४-४९८

	माह	पृष्ठ
पटेल, जवाभाई झवेरभाई		
गोबर गैस सयत्र एक अध्ययन	सितम्बर १९६४	७९७-७९९
गोबर गैस सयत्र विभिन्न उपयोग और समाज पर प्रभाव	अगस्त १९६४	७२२-७२३
पटेल, झवेरभाई		
खादी का मिशन	अक्तूबर १९६३	४८-५५
पद्मनाभन, वेंकटेशन्		
ग्रामीण उद्योग और लोकतांत्रिक समाजवाद	सितम्बर १९६४	७९०-७९३
पन्त, यादव प्रसाद		
नेपाल की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	नवम्बर १९६३	१५२-१५७
प्रभाकर, पुरुषोत्तम		
पचायत राज	मई १९६४	५५९-५६२
पाटिल, रामकृष्णराव कृष्णराव		
खादी का भविष्य	अक्तूबर १९६३	४३-४७
पाण्डेय, कमलेश्वरानन्द		
खादी आन्दोलन का बुनियादी विचार	मार्च १९६४	४३२-४३४
पिछोलिया, खेमराज		
एक राजस्थानी गाँव में कुम्भकारी उद्योग	जून १९६४	६४१-६४२
पै, दत्तकुमार		
वस्त्र छपाई	अगस्त १९६४	७४६-७४७
बैट्रो, पेकल श्रीरामूल		
ऊनी और पशम वस्त्रों में सुधार के लिए भेड़-पालन	जुलाई १९६४	६७९-६८३
वस्त्र रंगाई के सिद्धान्त	दिसम्बर १९६३	२५४-२५९
बनर्जी, कमल		
मुशिदाबाद का सूती और रेशमी खादी उद्योग	अगस्त १९६४	७४२-७४५
मुशिदाबाद का हाथी दात शिल्प	मई १९६४	५६५-५६९
रेशम उद्योग व रेशम अनुसंधान	जनवरी १९६४	३१४-३१६
बराट, शिशिर कुमार		
हमारे हड्डी स्रोत	अक्तूबर १९६३	९७-९९
बसु, आशीश कुमार		
पश्चिम बंगाल के कुटीर शिल्प	फरवरी १९६४	३७३-३७४
बालसुब्रह्मण्यन, मगुदेसन		
आर्थिक विकास का साधन शिक्षा	नवम्बर १९६३	१७१-१७४
किसानों के लिए उर्वरक	अगस्त १९६४	७२४-७२५
बेग, नफीस		
पचायत राज और सामुदायिक विकास	फरवरी १९६४	३६२-३६४
बैकर, शकरलाल		
अम्बर की शक्यता	अक्तूबर १९६३	५६-६०
खादी उद्योग में वैज्ञानिक दृष्टि	अप्रैल १९६४	४९०-४९३

	माह	पृष्ठ
बोस, शैलेश कुमार बिहार में आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और रोजगारी	नवम्बर १९६३	१६१-१७०
भट, माखन लाल जम्मू और कश्मीर का पशुधन चन्द समस्याएँ जम्मू और कश्मीर में रेशम उत्पादन का विकास पाली में एकमुश्त कार्यक्रम	सितम्बर १९६४ जुलाई १९६४ जनवरी १९६४	८०२-८०९ ६६९-६७८ ३०७-३१३
भटनागर, इन्दर मोहनलाल कश्मीरी 'गब्बे' की कहानी	जून १९६४	६४३-६४४
भारतानन्द (मॉरिस फ्रिडमन) सूक्ष्म प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान	मई १९६४	५४६-५५२
भास्कर, त्रिलोकनाथ औद्योगिक सहकारिताएँ और लोकतान्त्रिक समाजवाद	अगस्त १९६४	७४८-७५१
मथाई, पुतुपरम्बिल मथाई ग्रामीण औद्योगीकरण	अप्रैल १९६४	४८१-४८४
मल्होत्रा, दया कृष्ण लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी	अप्रैल १९६४	४७८-४८०
महाजन, विद्या सागर आय वितरण पर एक दृष्टि	जनवरी १९६४	२९२-२९९
महेता, रतिलाल सहकार पर वैकुण्ठभाई के विचार	जुलाई १९६४	७०६-७०८
मिर्जा, मसूद अली औद्योगिक सहकारी समितियाँ	अप्रैल १९६४	५०२-५०४
मिरमिरा, श्रीनिवासमूर्ति कृष्णमूर्ति ग्रामीण कुम्हारी उद्योग में चीनी मिट्टी के बर्तन	दिसम्बर १९६३	२४७-२४८
मित्र, ललित कुमार ग्राम और लघु उद्योगों के लिए संगठन	नवम्बर १९६३	१४६-१५१
मुकर्जी, ब्रह्मदेव गाँवों के लिए ऋण की व्यवस्था	अक्टूबर १९६३	२९-३५
मुखर्जी, चित्तप्रिय ग्रामीण रोजगारी और योजना	अक्टूबर १९६३	१००-११०
मुखर्जी, सुनील कुमार भारतीय आहार, औद्योगिकी और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	नवम्बर १९६३	१५८-१६०
मूर्ति, पेकनाला बाल कृष्ण लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों का सामान्य प्रबन्ध	अगस्त १९६४	७५६-७५८
मूर्ति, राम गोबर गैस सयंत्र एक अध्ययन (एस डी तेजनारायण के सहयोग से)	जुलाई १९६४	६९९-७०१

	माह	पृष्ठ
मेहता, बहराम होरमसजी आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामोद्योग	अक्तूबर १९६३	९०-९३
मेहता, वैकुण्ठ लल्लूभाई आर्थिक विकास पर प्रधान मंत्री के विचार आयोजन का गांधीवादी दृष्टिकोण इजरायल में कृषि-उद्योग समन्वय खादी और अर्थ-व्यवस्था खादी और ग्रामोद्योगों की प्रासंगिकता खादी कार्यक्रम और उसकी आलोचना गांधी सेवक समाज गाँव और शहर ग्रामीण औद्योगीकरण में समस्याएँ जवाहरलाल नेहरू नीरा बनाम ताड़ी परिगणित जातियो व परिगणित जन-जातियों की अवस्था में सुधार बुनाई उपदान योजना के निहितार्थ	अगस्त १९६४ अक्तूबर १९६३ सितम्बर १९६४ फरवरी १९६४ जनवरी १९६४ अप्रैल १९६४ मार्च १९६४ जून १९६४ मई १९६४ जून १९६४ जुलाई १९६४ मार्च १९६४ दिसम्बर १९६३	७१९-७२१ ११-१५ ७७५-७७७ ३४६-३४९ २७६-२७९ ४६७-४७२ ४५४-४५६ ५९९-६०२ ५१९-५२३ अतिरिक्त पृष्ठ ६४७-६४९ ३९८-४०० २०७-२१०
मोहसीन, मुहम्मद आर्थिक प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था	सितम्बर १९६४	७८५-७८९
यशवत, तण्डलम सोमसुन्दर अन्नोपभोग और घटिया से बढ़िया अनाज की ओर : एक अध्ययन (रा राजगोपालन के सहयोग से) मद्रास के एक गाँव का आर्थिक चित्र (ने. सु. तिरुवैकटाचारी के सहयोग से) सामाजिक अनुसंधान की भूमिका	जून १९६४ सितम्बर १९६४ जनवरी १९६४	६२३-६३० ८१०-८१२ ३१७-३१८
रंगनाथ, श्रीपति आन्ध्र प्रदेश की दस्तकारियाँ ग्रामोद्योगीकरण का बिक्री विषयक पहलू	अप्रैल १९६४ नवम्बर १९६३	५०७-५०९ १९९-२०१
रहमान, हबीबुर पचायत राज के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन	जुलाई १९६४	६६०-६६२
राघबलू, चित्तूरी वेकट लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण	जून १९६४	६०८-६१३
राजगोपालन, रामकृष्णन अन्नोपभोग और घटिया से बढ़िया अनाज की ओर. एक अध्ययन (तण्डलम सो यशवत के सहयोग से)	जून १९६४	६२३-६३०

	माह	पृष्ठ
राजग्या, जे.		
आधुनिक मधुमक्खी-पालन	मार्च १९६४	४२९-४३१
रायचौधरी, गौरी शंकर		
भारत पर नयी दृष्टि	अक्तूबर १९६३	११७-११९
राव, पुल्लै विश्वनाथ श्रीकण्ठ		
मितव्ययी तिलहन एकत्रण की ओर	अक्तूबर १९६३	१३१-१३४
राव, पोन्नूसामी कुण्डु		
बैलो की आँतो का निर्यात व्यापार	मई १९६४	५६३-५६४
राव, भास्कर यशवन्त		
उन्नत धान-कुटाई चक्की		
(रा. कृ. श्रीवास्तव और एस वाय नन्दनवार के सहयोग से)	अगस्त १९६४	७२६
राव, मंजेश्वर सदाशिव		
ग्रामीण औद्योगीकरण में वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं की भूमिका	अक्तूबर १९६३	१११-११६
हाथ कागज उद्योग में निस्पंदक पत्र का उत्पादन		
(बालचन्द्र मा. अग्शीकर के सहयोग से)	फरवरी १९६४	३५०-३५३
वान्देकर, दत्तात्रेय नाथोबा		
आदिवासियों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर	जनवरी १९६४	३००-३०२
ग्रामीण क्षेत्रों में गैस-सयंत्र	अप्रैल १९६४	४९९-५०१
वासनीय, प्रकाश चन्द्र		
चीनी का श्रोत ताड़	मई १९६४	५५३-५५८
वासुदेवराजू, वैट्टेकरनपुद्दूर आरुमुगम्		
ईट और चूना उद्योग का एक अध्ययन	दिसम्बर १९६३	२६०-२६७
ग्रामीण औद्योगीकरण और भूमि सुधार	अगस्त १९६४	७५२-७५५
बिवेकानन्द		
दरिद्रता का अभिशाप	जनवरी १९६४	२६९-२७२
विश्वनाथन, हरिहरन		
मधुमक्खियाँ और परागाधान	मार्च १९६४	४२६-४२८
वीरराघवाचार, सरगुर मदभूषणम		
मैसूर में ग्राम्य जन-शक्ति परियोजनाएँ	मई १९६४	५३७-५४०

	माह	पृष्ठ
वैद्यनाथन, कोदण्डरामन		
समग्र विकास कार्यक्रम	अप्रैल १९६४	५०५-५०६
शनसुगम्, सोमसुन्दरम्		
विस्तार पद्धतियों का प्रयोग	जुलाई १९६४	६९७-६९८
शर्मा, युवेश चन्द्र		
भारतीय निर्यात व्यापार तीव्र विस्तार की आवश्यकता	अगस्त १९६४	७६२-७६५
शाह, बिमल		
वालोट महाल विकास योजना एक विवेचन	जनवरी १९६४	३०३-३०५
श्रीखण्डे, जागेइधर गोपाल		
• ग्राम सफाई	फरवरी १९६४	३८७-३८८
मिट्टी की अभिव्यक्तता और अपारदर्शी काचन चन्द प्रयोग (यशवत वि खेर के सहयोग से)	जून १९६४	६२१-६२२
श्रीदेवी, श्रीपति		
स्त्री-शिक्षा की समस्याएँ	अक्तूबर १९६३	१२०-१२४
श्रीवास्तव, राम कृष्ण		
उन्नत धान-कुटाई चक्की (एस बाय. नन्दनवार और भा. य राव के सहयोग से)	अगस्त १९६४	७२६
वर्धा धानी से तेल सम्प्राप्ति (माधव रा देशपाण्डे के सहयोग से)	मई १९६४	५२४-५२६
शेट्टी, बन्दार बैकप्प		
मैसूर के गाँवों में प्रचलित काम-धधे	फरवरी १९६४	३५९-३६१
मैसूर के दो गाँवों में कर्जदारी	जुलाई १९६४	६६३-६६८
शेण्डे, सीताराम गंगाधर		
मधुमक्खी-पालन उद्योग समीक्षा	मार्च १९६४	४२१-४२२
सोवियत संघ में मधुमक्खी-पालन	दिसम्बर १९६३	२१८-२२३
सरकार, सुभाष चन्द्र		
अखाद्य तेल से विकेन्द्रित साबुन उत्पादन	सितम्बर १९६४	८२६-८३०
खादी-ग्रामोद्योग और प्रचार कार्य	दिसम्बर १९६३	२११-२१७
ग्राम्य जीवन में स्थिरता और परिवर्तन	जनवरी १९६४	३१९-३२५
जवाहरलाल नेहरू	जून १९६४	अतिरिक्त पृष्ठ
प्रचार की निरर्थकता	जुलाई १९६४	७०२-७०५
भारत में मधुमक्खी-पालन	मार्च १९६४	४१७-४२०
समृद्धि की द्विविधा	अक्तूबर १९६३	१३५-१३७

खादी ग्रामोद्योग

	माह	पृष्ठ
सहस्रबुद्धे, अनन्त वासुदेव खादी आन्दोलन मे क्रान्तिकारी परिवर्तन	मार्च १९६४	४०१-४०३
साठे, मधुसूदन दत्तात्रेय अहमदनगर जिले मे गाँवो का आर्थिक सर्वेक्षण और आयोजन	अगस्त १९६४	७२७-७३६
साहू, ध्वजा प्रसाद खादी किस ओर ?	अक्तूबर १९६३	४१-४२
सिंह, गुलजार अभिनव भेड-पालन	जून १९६४	६४२-६४३
सिंह, तरलोचन भारत मे तिलहन पेराई उद्योग	मई १९६४	५७०-५७३
सिंह, राम सुभग मधुमक्खी-पालन उद्योग की समस्याएँ	मार्च १९६४	४०४-४०७
सिंह, त्रिभुवन नारायण ग्रामीण क्षेत्रो मे उद्योग कार्यक्रम	अक्तूबर १९६३	२६-२८
ग्रामोद्योगो के लिए मध्यम प्रौद्योगिकी	अप्रैल १९६४	४७३-४७७
सिखर, अपर्णा सजीव कृषि मे निम्बौरी के गूदे और खली का उपयोग	अगस्त १९६४	७६०-७६१
सीतारामय्या, वेदनभट्टल उडीसा की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और खादी तथा ग्रामोद्योग	नवम्बर १९६३	१७७-१८३
सुन्दरम्, जोसेफ डुरै- यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक	अक्तूबर १९६३	६१-६९
सुन्दरम्, तोबलै मीनाक्षी धान की हाथ कुटाई व सेलीकरण	मई १९६४	५७९-५८०
सेन, सत्य रंजन तृतीय पंच वर्षीय योजना मे रेशम खादी उद्योग	नवम्बर १९६३	१८४-१८६
हुसैन, इस्तफा पूर्वी उत्तर प्रदेश की अविकसित अर्थ-व्यवस्था	मार्च १९६४	४३५-४४०

सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए 'ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५९ से प्रकाशित तथा मुद्रित । मुद्रण-स्थळ : एसोसिएटेड एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ५०५, तारदेव आर्थर रोड, बम्बई-१५



	पृष्ठ
दशम वर्ष	१
भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का स्वरूप	—उच्चरंगराय न. ठेबर ५
आयोजन का गांधीवादी दृष्टिकोण	—वैकुण्ठ ल. मेहता ११
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के चन्द पहलू	—मोरारजी देसाई १६
शैक्षणिक प्रगति तथा औद्योगीकरण	—कन्दस्वामी अरुणाचलम् २०
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग कार्यक्रम	—त्रिभुवन नारायण सिंह २६
गाँवों के लिए ऋण की व्यवस्था	—ब्रह्मदेव मुकर्जी २९
हमारी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर खादी का प्रभाव	—अरुण चन्द्र गुहा ३६
खादी किस ओर ?	—ध्वजा प्रसाद साहू ४१
खादी का भविष्य	—रामकृष्णराव कृ. पाटिल ४३

(अगले पृष्ठ पर)

सम्पादक सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा 'ग्रामोद्योग', इर्ला, बम्बई-५६ से मुद्रित और प्रकाशित। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की पत्रिका 'खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थशास्त्र-विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ मद्धर्ष विचार किया जायेगा। स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। लेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोद्योग', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। टेलिफोन नं. ८६७७३।

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो।

वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ नये पैसे। इस अंक के दो रुपये। चन्दों की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए अस्तिष्ठेष्ट एकाउण्ट्स ऑफिसर (कैश), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोद्योग', इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६।

विषय सूची

(पिछले पृष्ठ से)

खादी का मिशन	—अवेरभाई पटेल	४८
अम्बर की शक्यता	—शंकरलाल बैकर	५६
यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक	—जोसेफ दु. सुन्दरम्	६१
गत पन्द्रह वर्ष में रोजगारी व बेरोजगारी	—भगवन्त नागेश दातार	७०
भारत में पूँजी संचयन और निवेश	—अमृतलाल दत्त	७६
आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामोद्योग	—बहराम होरमसजी मेहता	९०
कृषिक अनुसंधान और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	—अब्दुल रहीम खॉ	९४
हमारे हड्डी स्रोत	—शिशिर कुमार बराट	९७
ग्रामीण रोजगारी और योजना	—चितप्रिय मुखर्जी	१००
ग्रामीण औद्योगीकरण में वैज्ञानिकों और अभियंताओं की भूमिका	—मंजेश्वर शदाशिव राव	१११
भारत पर नयी दृष्टि	—गौरी शंकर रायचौधरी	११७
स्त्री शिक्षा की समस्याएँ	—श्रीपति श्रीदेवी	१२०
बंगाल में शहरीकरण के कुछ पहलू	—मीरा गुहा	१२५
मितव्ययी तिलहन एकत्रण की ओर	—पु. वि. श्रीकण्ठ राव	१३१
समृद्धि की दुविधा	—शुभाष चन्द्र शरकार	१३५
पुस्तक समीक्षा :		१३८

एस्पेक्ट्स ऑफ इकनॉमिक चेंज एण्ड पॉलिसी इन इण्डिया १८००-१९६०—बी. वी. भट्ट।

एक्शन रिसर्च एण्ड इट्स इम्पॉट्स इन एन अण्डर-डेवलप्ड इकनॉमी—प्लानिंग रिसर्च एण्ड पब्लिक इन्स्टीट्यूट, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

इकनॉमिक अफेयर्स (अर्थशास्त्र विषयक मासिक), योजना अंक—हिमासूर राय, कलकत्ता।

कोऑपरेटिव पॉलिसी एण्ड प्रोग्रैम्स—नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया, नयी दिल्ली।

कोऑपरेशन अँज ए रेमेडी फॉर रूरल पावर्टी—एम. नुरल हक, ईन्ट पाकिस्तान कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, ढाका।

इस अंक के लेखक

उछरंगराय नवलशंकर डेबर	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष ।
वैकुण्ठ लल्लूभाई मेहता	—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।
मोरारजी रणछोडजी देसाई	—भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री, मसद सदस्य ।
कन्दस्वामी अरुणाचलम्	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के उपाध्यक्ष ।
त्रिभुवन नारायण सिंह	—योजना आयोग के सदस्य ।
ब्रह्मदेव मुकुर्जी	—वर्म्बई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ।
अरुण चन्द्र गुहा	—संसद सदस्य, लोक सभा की अनुमान समिति के अध्यक्ष ।
ध्वजा प्रसाद साहू	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के सदस्य ।
रामकृष्णराव कृष्णराव पाटिल	—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।
शबेरभाई पुरुषोत्तमभाई पटेल	—खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य ।
शकरलाल घेलाभाई बैंकर	—प्रख्यात अनुभवी रचनात्मक कार्यकर्ता ।
जोसेफ डुरै सुन्दरम्	—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के भूतपूर्व अध्यक्ष जिनका निदेशन अ. १०० स्थित 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक्स' के मेनेजरी ।
भगवन्त नागेश दातार	—भारत सरकार के नयी दिल्ली स्थित योजना आयोग में भूमि रोजगारी प्रमुख ।

(अगले पृष्ठ पर)

इस अंक के लेखक
(पिछले पृष्ठ से)

अमृतलाल दत्त

—बम्बई स्थित टैरिफ कमीशन में सहायक अनुसंधान निर्देशक ।

बहराम होरमसजी मेहता

—टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेस में रिसर्च प्रोफेसर, 'इण्टेग्रेटेड प्रोग्रैम्स ऑफ सोशल सर्विसेस एण्ड एज्युकेशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर' के गोडवाना केन्द्र के निर्देशक ।

अब्दुर रहीम खॉ

—नयी दिल्ली स्थित भारतीय कृषिक अनुसंधान संस्था में कृषि विस्तार विभाग के अध्यक्ष ।

शिशिर कुमार बराट

—मद्रास स्थित केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्था में सहायक निर्देशक, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की चर्मोद्योग सलाहकार समिति के सदस्य ।

चित्तप्रिय मुखर्जी

—श्रीनिकेतन स्थित 'रूरल हायर इन्स्टीट्यूट' में सहकार के लेक्चरर ।

मजेश्वर सदाशिव राव

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की ग्रामीण इंजीनियरिंग शाखा के निर्देशक ।

गौरी शंकर रायचौधरी

—दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के लेक्चरर ।

श्रीपति श्रीदेवी

—हैदराबाद स्थित महिला विश्वविद्यालय कालेज की आचार्या ।

मीरा गुहा

—कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल की लेक्चरर ।

पुल्लै विश्वनाथ श्रीकण्ठ राव

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में अखाद्य तेल और साबुन उद्योग निर्देशक ।

सुभाष चन्द्र सरकार

—खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित 'खादी ग्रामोद्योग' तथा 'जागृति' के सम्पादक ।

दशम वर्ष

प्रस्तुत अंक के साथ खादी ग्रामोद्योग अपने जीवन के दसवें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। गाँवों में परम्परागत उद्योगों में लगे, यहाँ-वहाँ बिखरे हुए रूप में बसे हुए असंगठित कारीगरों को संगठित करने और तकनीकल प्रशिक्षण तथा वित्तीय एवम् अन्य प्रकार की सहायता के जरिये उनकी हालत सुधारने में मदद करने हेतु भारत सरकार ने अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना की, उसके लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। निश्चय ही किसी संस्था को अपना संगठन स्थापित करने में कुछ समय लगता है—विशेष कर उस अवस्था में जबकि उसका कार्यक्षेत्र या स्वरूप अखिल भारतीय स्तर का हो। अतएव एक माने में खादी ग्रामोद्योग का दसवाँ वर्ष खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के सुव्यवस्थित प्रयासों का दशम वर्ष समझा जा सकता है।

राष्ट्र विकास के लिए पिछला दशक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस दशक में राजनीतिक तथा आर्थिक एकीकरण और पूर्णिकरण अर्थात् समा-कलन हुआ है एवम् जनता की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली के लिए सुनियोजित उपाय काम में लाये गये हैं। इसी काल में पंचायत राज की स्थापना के जरिये, निर्णय करने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की आवाज को साथ लेकर चलने के बड़े सोचे-समझे कदम भी उठाये गये। आयोजन पर जोर देना इस दशक की प्रबल प्रवृत्ति रही है।

खादी व ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं का मूल्यांकन अर्थ-व्यवस्था की सामान्य प्रगति के सदर्भ में करना पड़ेगा। अर्थ-व्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्र में प्रयास करने के बावजूद सामान्य चित्र यह रहा है कि विकास व परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत मन्द रही है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और

उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्नों का कोई विशेष प्रत्युत्तर नहीं मिला। चूँकि अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है—वैसे सामान्य आबादी के सम्बन्ध में भी यह सच है—इसलिए कृषि में मन्द विकास की प्रतिष्ठाया गाँवों में चलनेवाले अन्यान्य काम-धंधों पर भी पड़ने लगी है।

सामान्यतः विकास की प्रक्रिया के साथ कदम मिला कर चलने में कृषि की असफलता से उन कठिनाइयों का प्रतिबिम्ब सामने आता है, जिनके साथ विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था को लोहा लेना पड़ा। खादी व ग्रामोद्योगों का काम एक लाख से भी अधिक गाँवों में फैला हुआ है। दस वर्ष पूर्व करीब दस हजार गाँवों तक ही इस कार्यक्रम का विस्तार था। खादी-उत्पादन (मय रेशमी, ऊनी व अम्बर खादी) में ५५९ प्रति शत से भी अधिक वृद्धि हुई है। यह उत्पादन १९५३-५४ में १,१५,६३,००० वर्ग गज था, जो १९६१-६२ में ७,६२,०२,००० वर्ग गज तक जा पहुँचा। इसी प्रकार रोजगारी के क्षेत्र में भी ३६० प्रति शत से अधिक वृद्धि हुई। पूर्ववर्ती वर्ष में ३,७९,००० व्यक्तियों को रोजगारी मिली थी तथा अनुवर्ती में १७,४६,००० को। अन्य ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों ने १९६१-६२ में कुल २३,६०,००० व्यक्तियों को रोजगारी प्रदान की, जिनमें से ७४ प्रति शत अकेले खादी उद्योग में लगे थे। इसी प्रकार नौ वर्ष की अवधि में खादी की बिक्री में चौदह गुनी वृद्धि हुई। पाँच लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगारी प्रदान की गयी।

निस्संदेह खादी व अन्य परम्परागत ग्रामोद्योगों में व्यक्ति को पारिश्रमिक कम मिलता है अर्थात् इनसे उसे कम ही आमदनी होती है और रोजगारी प्राप्ति के अन्य कई क्षेत्रों में मिलनेवाले पारिश्रमिक की तुलना में वे ठहर

नहीं पाते। किन्तु यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी को कहीं अन्यत्र अच्छी रोजगारी मिलती है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह इन उद्योगों को अपनाये ही। गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, “हाथ कटाई किसी भी उद्योग की विनाशक नहीं है। मैंने हाथ कटाई के खातिर एक भी उपयोगी प्राणदायक औद्योगिक प्रवृत्ति को छोड़ने की कल्पना तक नहीं की, सलाह देना तो दूर रहा।” इस गांधीवादी दृष्टिकोण से पराङ्मुखता नहीं आयी है। इस आर्थिक वास्तविकता की स्पष्ट प्रतिछाया गत २६ अगस्त को केन्द्रीय योजना मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया उसमें मिलती है। उस वक्तव्य में यह बताया गया था कि देश की जन-संख्या में नितल श्रेणी के दस प्रतिशत व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय देहातो में आठ रुपये और शहरी में दस रुपये है। इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन व्यय ४ ३ आने (२७ नये पैसे से कुछ अधिक) और शहरी क्षेत्रों में तेतीस नये पैसे है। उक्त वक्तव्य के अनुसार देहाती क्षेत्रों की सत्तर प्रतिशत आबादी प्रति दिन पचास नये पैसे से कम ही खर्च कर सकती है। और, देश की अस्सी प्रतिशत से अधिक जन-संख्या गाँवों में रहती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि २५ करोड़ १९ लाख व्यक्तियों के पास प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने के लिए पचास नये पैसे भी नहीं हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ग्यारहवें दौर के अनुसार ग्रामीण आबादी का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च १६ ९७ रुपये था यानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन ५६ नये पैसे से कुछ ही ऊपर। फिर, एक से दूसरे प्रदेश में पर्याप्त भिन्नता है, जैसे मध्यवर्ती भारत में १४ ९१ रुपये मासिक और पश्चिमोत्तर

भारत में २१ ७५ रुपये। शहरी क्षेत्रों की आय के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का भिन्नत्व दृष्टव्य है।

योजना मन्त्री द्वारा उद्धृत आकड़े सितम्बर १९६१ से जुलाई १९६२ तक की अवधि से सम्बन्धित थे, जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का सत्रहवाँ दौर पूर्ण हुआ था। यहाँ यह स्मरण करवाया जा सकता है कि १९५५ में हुए सर्वेक्षण (नवम दौर) के प्रति व्यक्ति औसत सम्बन्धी आकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में २० करोड़ व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय १७५ रुपये थी, जिसके माने हैं पचास नये पैसे रोजाना से कम। इस प्रकार १९५५ और १९६२ के बीच इस न्यून आय वर्ग में पाँच करोड़ व्यक्ति बढ़े हैं। इसे आर्थिक प्रगति का द्योतक नहीं समझा जा सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि जनता को रोजगारी के ऐसे अवसर उपलब्ध करवाये जा सकें कि उससे वह प्रति व्यक्ति प्रति दिन पचास नये पैसे से अधिक कमाई करने में समर्थ हो तो प्रयास काफी प्रशंसनीय होगा। इस दृष्टि से मूल्यांकन करने से खादी और ग्रामोद्योगों का सही स्थान सामने आ जायेगा। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के प्रति आलोचकों ने जो धारणा बनायी अथवा उसका जो चित्र प्रस्तुत किया है उसके विपरीत न्यूनतम आय वर्ग में आनेवाले सूतकारों की आय बढ़ाने में सहायता देने के प्रति वह अनभिज्ञ अथवा असावधान नहीं है। कमीशन ने ऐसा चरखा प्रचलित करने का निर्णय किया है, जिससे सूतकार प्रति दिन एक रुपया कमा सकेंगे। यह नमूना ज्यों ही परिपूर्ण होगा, उसका क्षेत्र में प्रचलन किया जायेगा।

प्रायः सवालान उठाये जाते हैं कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव

पडा है। प्रथम पंच वर्षीय योजनावधि में खादी और ग्रामोद्योगों के लिए १४ करोड़ ८२ लाख रुपये निर्धारित किये गये अर्थात् योजना के लिए जो कुल प्रावधान था उसके ०.४४ प्रति शत के बराबर इन उद्योगों को दिया गया। द्वितीय योजना में खादी व ग्रामोद्योगों के लिए ८४ करोड़ रुपये का प्रावधान (योजना के कुल निर्धारण का १.२४ प्रति शत) रखा गया। इनके लिए तीसरी योजना के अन्तर्गत रखा गया ९२ करोड़ ४० लाख रुपये का प्रावधान कुल निर्धारण का ०.७८ प्रति शत है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि तीनों योजनाओं में कुल २ खरब १९ अरब १० करोड़ रुपये के निर्धारण में से खादी और ग्रामोद्योगों के विकासार्थ मात्र १ अरब ९१ करोड़ २२ लाख रुपये यानी कुल की करीब ०.८७ प्रति शत निधि ही दी गयी। कुल आयोजित परिव्यय के एक प्रति शत से भी कम व्यय के साथ किसी कार्यक्रम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की शायद ही अपेक्षा की जा सके। देश में कुछ विशिष्ट क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ कार्यक्रम के प्रभाव का समुचित अध्ययन किया जा सकता है। और फिर, कार्यक्रम के लाभदायक प्रभाव का स्थायित्व व्यापक राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी यात्रिक इकाइयों की स्थापना अथवा नीति परिवर्तन के कारण कार्यक्रम छिन्न-भिन्न हो सकता है, जहाँ कि वह सफलतापूर्वक संचालित, कार्यान्वित किया जा चुका है। गन्ना-पूर्ति का धारा-प्रवाह चीनी उत्पादन की ओर मोड़ने के हाल ही के निर्णय से गड-उत्पादक को खतरा पैदा हो गया है।

खादी तथा ग्रामोद्योगों की प्रकृति अथवा स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि उस कारण ग्रामीण समुदाय के अपेक्षाकृत पिछड़े हुए वर्ग के साथ

व्यवहार करना खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए आवश्यक हो जाता है अर्थात् उसे ग्रामीण समाज के पिछड़े हुए वर्गों में काम करना पड़ता है, जो आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर है। कार्यक्रम की व्यवस्था यानी उसका प्रबन्ध करने में आनेवाली विभिन्न समस्याएँ (जरूरत-मन्द व्यक्तियों को वित्त उपलब्ध कराना और वह भी उसकी सुरक्षा पर बिना कोई आघात पहुँचाये, उपयुक्त उपकरण मुहैया करना, साधन-सरजाम की मरम्मत के लिए सुविधाएँ प्राप्त करवाना, ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उन्हें ऐसे उपकरणों का व्यवहार करने के लिए तैयार करना, हो सकता है जिनके वे अभ्यस्त न हों अथवा जिनके लिए वे नये हों, उत्पादन की देखभाल करना, उत्पादनों की बिक्री-व्यवस्था करना और वह भी दूर-दूर, अलग-थलग रूप में बसे गाँवों से इकट्ठे करके; तथा अन्य ऐसी ही अनेक बातों की सार-सम्भाल करना) विचार कर देखने पर अपनी सही विशालता और जटिलता के साथ सामने आयेंगी, जो सर्वोत्तम अभिक्रम तथा इरादों को भी विचलित कर देने के लिए पर्याप्त है।

इस समस्याओं का कोई सरल समाधान नहीं है तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अतिरिक्त अन्य कई संस्थाएँ भी उन्हें हल करने में जुटी हैं, पर किसी को भी अधिक सफलता नहीं मिली है। और फिर, यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कमीशन प्रायः प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता। कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल, सहकारी समितियाँ तथा समिति पजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत संस्थाएँ करती हैं। कमीशन के प्रमुख कार्य वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन व समितियों के कार्यकर्त्ताओं

तथा कारीगरो के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान करने सम्बन्धी है। अपने काम में समितियाँ किस हद तक सफल होती हैं, यह अनेक बातों पर निर्भर करता है, उदाहरणार्थ उनके पास कैसे, कितने उद्यमशील, साहसी व व्यवस्थापकीय योग्यता रखनेवाले कार्यकर्त्ता हैं, कच्चा माल प्राप्त करने और अपने उत्पादनों की बिक्री करने में बाजार में आनेवाली घट-बढ़ या उतार-चढ़ाव का सामना करने की उनमें कितनी दक्षता व कौशल है, आदि।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पिछले दशक में जो प्रयास किये गये उनसे ऐसी बात नहीं है कि अच्छे परिणाम विल्कुल ही प्राप्त न हुए हों। किन्तु उस पर ही परितुष्ट हो कर बैठ जाने या काम में शिथिलता आने देने का अवसर नहीं है। कार्यक्रम का संचालन-क्षेत्र विस्तृत करने और ग्रामीणों के लिए उसकी सार्थकता बढ़ाने हेतु कमीशन में अधिक व बेहतरीन कार्य पर अनवरत जोर दिया जाता है। कमीशन ग्रामीण क्षेत्रों में काम करनेवाले अन्य माध्यमों और अपनी कार्यशीलताओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा है, ताकि जो प्रयास किये जायँ उनसे अधिकाधिक फल प्राप्त किये जा सकें। समन्वय की आवश्यकता के प्रति जागरूकता ही नया मोड़ कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में मार्गदर्शक भावना है। ग्राम पुनर्निर्माण की सर्वाधिक कठिन समस्याओं से मुटभेड़ लेने में, यह कहे कि निरन्तर सजगता और आत्म-समीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है अर्थात् उक्त दोनों बातों के महत्व की शायद ही अतिशयोक्ति हो सके। जहाँ खादी और ग्रामोद्योगों की अपूर्ण ज्ञान पर आधारित आलोचना को, सही स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, रोकना है वहाँ उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने से इन्कार करना अनुचित होगा। खादी व

ग्रामोद्योगों के विकास कार्य में लगे कार्यकर्त्ता यदि परिपूर्ण जानकारी में युक्त और पक्षपात-विहीन दृष्टि से विभिन्न विकल्पों पर विचार करें तो ही गलतियों से बचा जा कर सही मार्ग ढूँढा जा सकता है। अतएव प्रस्तुत अंक में—ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सामान्य मूल्यांकन प्रस्तुत करना जिसका उद्देश्य है—कार्यक्रम और कमीशन की आलोचना को दूर रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

पत्रिका का उद्देश्य इसके प्रथम अंक में श्री वैकुण्ठ ल मेहता ने इस प्रकार बताया था “किन्तु राज्य की सहानुभूति और सहायता जरूरी होने पर भी मण्डल (अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल, जिसके उत्तराधिकारी के रूप में अब खादी और ग्रामोद्योग कमीशन है) जो पुनर्गठन करके उसके द्वारा व्यापक रूप में लोगों को रोजी देना चाहता है, वह तभी सम्भव है जबकि समाज का विचारक वर्ग, जो सार्वजनिक मामलों के मार्ग पर अपना अधिक प्रभाव रखता है, हमारे आर्थिक जीवन में खादी और ग्रामोद्योगों का महत्व समझे तथा उनकी कद्र करें। अतः समाज के इस वर्ग के समक्ष खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन का सही चित्र प्रस्तुत करना और उसके प्रति रुचि जागृत कर उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना मण्डल का एक सर्व प्रमुख कार्य है। गांधीजी ने हमें भारतीय अर्थनीति की बुनियाद का जो अमूल्य पाठ सिखाया है उसे अगर हम भूल गये तो हमारा सामाजिक ढाँचा छिन्न-भिन्न हो जायगा।” आज भी हमारा उद्देश्य यही है।

जनता के रहन-सहन की अवस्थाओं में सुधार करने के लिए किसी भी मौलिक यानी विशुद्ध कार्यक्रम में ग्रामोद्योगों की अनुप्रासगिकता तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति में आनेवाली जिन महान समस्याओं से लोहा लेना पड़ता है उसका यदि इस अंक से तनिक भी बेहतरीन अहसास हो जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा परिश्रम सार्थक सिद्ध हुआ। ●

भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का स्वरूप

उद्धरंगराय न. डेवर

भारत में पायी जानेवाली अनेक असमानताओं का मूल है हमारी समाज-व्यवस्था, जो युगयुगान्तरों से विशेषाधिकारो को पनपाती रही है। पिछले पन्द्रह वर्ष की अवधि में हुए अनेक प्रयासों के बावजूद देश में आज जो हालात हैं, वे सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में उत्साहजनक नहीं हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में आज घोर गरीबी का बोलबाला है। तीस प्रति शत आबादी के सामने तो आज जीवन-मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ है। असमानताएँ दूर करने का संघर्ष हमारी विशाल जन-संख्या के लिए अपना अस्तित्व बनाये रखने का संघर्ष है। अर्थ-व्यवस्था के इस असंतुलन को कम करने में खादी-ग्रामोद्योग तथा पशु-पालन से सहायता मिलेगी।

आय और सम्पत्ति के क्षेत्र में पायी जानेवाली असमानताओं के लिए अनेक बातें जिम्मेदार हैं। कुछ असमानताएँ व्यक्तिगत कारणों से हैं। प्रकृति ने हम सबको एक समान नहीं बनाया है। व्यक्ति-व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भिन्न होती है। हृदय और मस्तिष्क के गुणों से कुछ अन्य पहलुओं का भी सम्बन्ध होता है। जीवन में व्यक्ति के स्थान पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। साहसिक कार्य करने की भावना की भी अपनी भूमिका है। इन सब गुणों से युक्त व्यक्ति का पलड़ा अन्य लोगों से भारी होता है। इन सबसे कुछ असमानताएँ आया करती हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

फिर भी, कुछ असमानताएँ ऐसी हैं जो आपत्तिजनक हैं। उन्हें रोकना अथवा दूर करना होगा। व्यक्तिगत गुणों का इन असमानताओं से शायद ही कोई सरोकार हो। वे ऐसे कारणों से पैदा होती हैं जिनके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से श्रेय नहीं ले सकता। उनका उद्गम जन्म, वर्ग, जाति, धार्मिक पद, धार्मिक व्यवस्था यानी धर्मसत्ता, पेशे तथा अन्य बाह्य पहलुओं में है। सम्पन्न घर में पैदा हुआ एक मूढमति भी धनाढ्य है। इसलिए नहीं कि उसमें कुछ व्यक्तिगत गुण हैं, जिनसे वह उसके पास जो धन है उसका अधिकारी है, बल्कि इसलिए कि वह एक समृद्ध बाप का बेटा है। सामन्तशाही व्यवस्था में एक सामन्त के

लड़को को स्वतः भूमि मिल जाती है। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि वे संयोगवश एक सामन्त के बेटे हैं। जातिवादी दृष्टिकोण के कारण एक हरिजन सदैव ही घाटे में रहता है। पण्डे-पुजारियों की प्रधानता के युग में धर्म ने भी उक्त सदर्थ में अपनी भूमिका अदा की है। कुछ पेशे ऐसे हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है और समाज के प्रति जो भी सेवा वे करें उसके बदले में उन्हें सभी प्रकार से मोटी आमदनी होती है।

विषम समाज व्यवस्था

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि चन्द विशेषाधिकृत पद स्वतः ही कुछ लाभ प्रदान करते हैं, फिर चाहे वे पद सामाजिक कारणों से हो अथवा आर्थिक, राजनीतिक या धर्मसत्ता के कारण। इसका कारण है समाज-व्यवस्था का स्वरूप। समाज उक्त विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है और उनसे विहीन व्यक्तियों के दावों की अवहेलना करता है। भारत में प्रचलित अनेक असमानताओं का मूल समाज-व्यवस्था है, जिसमें युगयुगान्तरों से ऐसे विशेषाधिकारों का पोषण होता रहा है, जिनसे चन्द व्यक्तियों अथवा वर्गों को लाभ प्राप्त होता है, जबकि दूसरों को अधिकारों या अवसरों से वंचित रखा जाता है। फलस्वरूप भारत में आय तथा संपत्ति के क्षेत्र में उस सीमा तक असमानताएँ

पैदा हुई है, जिस सीमा तक समार के किसी अन्य सगठित समाज में शायद ही मिले।

२

विशेषाधिकृत वर्ग

भारत का जो चित्र आज १९६३ में है वह १९४७ से भिन्न है। सन् १९४७ में ऐसे सामाजिक वर्ग थे, जिन्हें तत्कालीन साम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन अधिकारों में जीवन में उन्हें किन्हीं प्रकार का स्थान यानी दर्जा प्राप्त था और समाज में उनकी आवाज थी। साथ ही साथ उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य भारतीय जनता उन अवसरों से वंचित थी, जिनसे वह अपना विकास करने में समर्थ बनती। अपनी प्रकृति से ही साम्राज्यवादी व्यवस्था शोषणकारी व्यवस्था थी। चन्द व्यक्तियों तक ही जीवन के व्यापक अवसर एकाधिकृत कर वह जीवित रही तथा पत्नी। साम्राज्यवादी वर्ग के बाद भूमिधारी अभिजात वर्ग आता है। उदाहरणार्थ, लगभग देश के एक-तिहाई भाग में भारतीय राजा-महाराजाओं को राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में वह प्रमुखता प्राप्त थी, जो अन्य किसी को उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार समाज-व्यवस्था से ऐसी सामाजिक प्रणाली अथवा गठन को पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके अन्तर्गत उनका बोलबाला था और जिसमें उनकी रियासतों में सर्वसाधारण को शायद ही कोई अवसर प्राप्त हो। राजकुमार का छोटा भाई उस समाज-व्यवस्था में जमींदार था। सामाजिक स्वरूप यानी संरचना में विशेषाधिकृत पद का दावा करके और अपने काश्तकार को प्रत्येक अवसर से वंचित करके उसने भी सामाजिक स्वरूप में असंतुलन ही पैदा किया। भारत में करीब तीन-चौथाई जन-संख्या काश्तकार है। उस वक्त वह उक्त समाज-व्यवस्था की शिकार थी।

उत्तराधिकारविहीन

अनुसूचित जातियाँ वह दूसरा वर्ग था, जिसे धर्म के नाम पर उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे।

परिगणित जन-जातियाँ एक अन्य वर्ग था, जिसे नीति-उन पर राजनीतिक पृथक्कत्व थोपने के लिए तत्कालीन साम्राज्यवादी सरकार द्वारा अख्तियार की गयी नीति-विषयक कारणों से उत्तराधिकारविहीन बनाया गया था। श्रमिक भी रोजगारी देनेवालों की दया पर निर्भर करते थे। स्थानिक बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी के कारण श्रमिकों के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि जो कुछ मजदूरी उन्हें प्रस्तुत की जाती हो उसे वे स्वीकार कर ले।

इन दो वर्गों-सामाजिक दृष्टि से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और शोषित वर्ग-के बीच मध्यम वर्ग था। वह भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से हीन जीवन व्यतीत कर रहा था।

गांधीजी का नेतृत्व

इस प्रकार की अप्राकृतिक स्थिति दीर्घ काल तक टिकनेवाली नहीं थी। शीघ्र ही जनता में नैराश्य के चिन्ह दिखायी पड़ने लगे, वह अपना अभिक्रम लाने लगी और कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि उसका परिपूर्ण नैतिक ह्रास हो चुका है। यह गांधीजी के नेतृत्व का चमत्कार ही था कि उन्होंने इस प्रकार के नैतिक ह्रास के वातावरण में नव आशा व साहस का संचार किया और जनता को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करने में सफल हुए, जिसकी प्राप्ति से इस देश तथा अन्य अनेक देशों पर साम्राज्यवादी व्यवस्था के अधिकार का खात्मा होना था।

३

उज्ज्वल भविष्य हेतु परिवर्तन

लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पन्द्रह वर्ष के शासन में भारत का चित्र बदल दिया है। साम्राज्यवाद का कब्जा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और भारतीय अर्थ-व्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से आज एक स्वतंत्र, अर्थ-व्यवस्था है। सरदार वल्लभभाई पटेल की राजनीतिक दूरदर्शिता ने देश को जमींदारों के चंगुल से भी

मुक्त कर दिया है। तुलनात्मक दृष्टि में, भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में भारतीय कृषक एक स्वतंत्र व्यक्ति है। साम्राज्यवादी सामन्तशाही व्यवस्था की समाप्ति में विशाल जनता के सामने अनेक अवसर आये हैं। अनुसूचित जातियाँ सम्भल रही हैं। परिगणित जन-जातियों का पृथक्करण समाप्त किया जा रहा है। कारखानों में काम करनेवाला मजदूर अपने हक के सम्बन्ध में आश्वस्त है। कृषिक तथा औद्योगिक दोनों ही प्रकार की आय में वृद्धि हुई है। शैक्षणिक अवसरों का काफी विशाल पैमाने पर विस्तार हुआ है। आज पहले के मुकाबले अधिक व्यक्तियों को जीवन सम्बन्धी सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पचायत राज सस्थाओं और सहकारी समितियों के माध्यम से भारत के सभी व्यक्तियों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के बचन को पूरा करने के लिए निष्ठापूर्ण तथा हार्दिक प्रयत्न किया जा रहा है। जनता में एक नया जागरण पैदा हुआ है, जिससे उसमें नये अभिक्रम का सृजन हो रहा है और जीवन के नव अवसर सामने आ रहे हैं। न्याय का यह तकाजा है कि जिन्होंने यह सब सम्भव बनाया है, उन्हें उचित श्रेय मिले।

४

कमियाँ

कुछ दिशाओं में कमियाँ हैं। वे भी सब जगह नहीं हैं। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कमियाँ हैं। मैं नहीं सोचता कि जिन व्यक्तियों के हाथ में देश की बागडोर है, जो भावी भारत के निर्माता हैं, वे भी इससे इन्कार करेंगे कि कमियाँ हैं। मैं यह भी नहीं सोचता कि उन्हें ही इन कमियों के लिए उत्तरदायी ठहराना उचित अथवा समीचीन होगा। जबकि रचनात्मक योगदान के रूप में उनके आलोचकों ने कुछ भी नहीं किया, वहाँ यदि कुछ कहना ही हो तो हम यह कह सकते हैं कि, उन्होंने देश की पन्द्रह वर्ष तक सेवा की है, जिसके फलस्वरूप आज हमारे जीवन में नये अवसर आये हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने वे बाधाएँ दूर की हैं जो कल तक राष्ट्र की प्रगति में रोड़ा अटकाए हुए थी।

इन कमियों के सम्बन्ध में कुछ विचार करने का कारण यह है कि इन कमियों में भयानक नैतिक और सामाजिक बाते छिपी हैं। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कमियाँ ढूँढी जा सकती हैं। यह हमारा मौभाग्य है कि हमें गांधी जैसा महापुरुष मिला। वे एक आदर्शवादी थे, जिनमें सहज व्यावहारिक ज्ञान भरा पूरा था। कठोर परिश्रम और व्यक्तिगत त्याग द्वारा उन्होंने देश में अहम् के विचार से रहित होकर दलितों की सेवा करने का वातावरण निर्मित किया। उन्होंने वित्तीय उत्प्रेरणाओं का स्थान लेने हेतु आध्यात्मिक उत्प्रेरणाओं, मान्यताओं को लोक-प्रिय बनाया। उन्होंने सादगी का वातावरण निर्मित किया। राष्ट्र के गत १५ वर्षों के जीवन में सबसे बड़ी कमी इसी स्तर पर रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि में १९६३ के भारत का १९४७ अथवा उससे भी पहले के भारत से शायद ही कोई सम्बन्ध हो। आज त्यागमय वातावरण के स्थान पर 'अपनी रोटी के नीचे आँच लगाने' वाला वातावरण पाया जाता है। सेवा का स्थान 'लक्ष्मी' ने ले लिया है। सहकारी सिद्धान्त के स्थान पर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना प्रतिष्ठापित की जा रही है। व्यक्तियों अथवा समूहों के वस्तुपरक, निरपेक्ष, विचार का रूपान्तर हो गया है। देश आज एक ऐसे वातावरण में रह रहा है जिसमें आराम-तलबी तथा अहंकार का बोल-बाला है। समग्र चित्र ही अधिकाधिक अश्लील तथा अशोभनीय बनता जा रहा है और अपने आकर्षण व शोभा से विहीन हो रहा है। यह कहना गलत होगा कि यह बात राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो दूसरे पर उगली उठा सकता हो और उस पर उगली न उठे।

क्षमतायुक्त साधन से वंचित

हमारे राष्ट्रीय जीवन का जो भी क्षेत्र हो, गांधीजी के जीवन-मूल्यों का अनुकरण न करने और अन्य देशों के स्तर की नकल की कोशिश करते हुए, राष्ट्र ने अपने आपको अपेक्षाकृत एक महान शक्त अथवा क्षमतायुक्त साधन या उपादान से वंचित कर लिया है, जो उसके लिए इस यथार्थ जगत में भी अत्यधिक सहायक होता।

सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा का सिद्धान्त सर्वसाधारण और अभिजात वर्ग को तथा विभिन्न वर्गों और समुदायों के व्यक्तियों को एक साथ रखने, विवेकशील और अनपढ़ जनता को एक-दूसरे के निकट लाने, धनवानों को गरीबों के साथ और शिक्षित व्यक्तियों को अशिक्षित व्यक्तियों के साथ मिलाने के लिए एक जादू के रूप में काम कर रहा था। हम यह महसूस करना प्रारम्भ कर रहे थे कि हमने एक ऐसा समाज निर्मित किया है कि वह जीवन के नये मूल्यों—सहकार, सद्भावना, सहानुभूति, भ्रानृत्व भावना, पारस्परिक प्रेम और भारत के लाखों-करोड़ों दलितों की अवस्था मुधारने का प्रयत्न करने में ही रुचि रखने के मूल्य—से बंधा हुआ है, उन पर टिका हुआ है। इन मूल्यों ने हमें कुछ अनुशासन के सिद्धान्त भी दिये। यह अनुशासन नये ढंग का था, किन्तु उसने राष्ट्र को एक प्रकार का स्वाभिमान और प्रतिष्ठा प्रदान की। उन मूल्यों और अनुशासन को जो सामाजिक मान्यता मिली, उससे साधारण आदमी को भी वे मूल्य तथा अनुशासन आसानी से अपनाने में सहायता मिली। उन मूल्यों को न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से बल्कि यथार्थ में भी आघात पहुँचा है। राष्ट्रीय जीवन आज फिर उन्ही मूल्यों की 'दया' पर निर्भर है, जो उसे पतन के गर्त में ले गये थे।

आर्थिक स्तर पर

आर्थिक स्तर पर भी कमियाँ रही हैं। भारत पूर्ण और अल्प-बेकारी के कारण दो करोड़ मनुष्य-दिनों की हानि उठा रहा है और उसे इस प्रकार की हानि काफी लम्बे समय तक उठानी पड़ेगी। समाज के निचले तबके में हमारी जन-संख्या के तीस प्रति शत को उस आमदनी पर सन्तोष करना पड़ता है, जो पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं समझी जा सकती और यद्यपि उसका स्तर १९४७ की अपेक्षा ऊँचा है तथा अनुक्रमिक रूप से ऊपर उठता ही जायेगा, लेकिन आगामी पच्चीस वर्ष या उससे भी ज्यादा समय तक मानवीय अस्तित्व की दृष्टि से वह पर्याप्त नहीं होगा। आज अधिकांश मध्यम वर्ग भार मय जीवन बिता रहा है और आगामी २०-३० वर्ष तक उसे

वैसी ही अवस्थाओं के अन्तर्गत रहना पड़ेगा। आय और सम्पत्ति के क्षेत्र में जो असमानताएँ हैं, उन पर इस सन्दर्भ में विचार करना होगा।

५

गरीबी की कहानी

इन असमानताओं का महत्व क्या है? कुछ चित्र मेरे सामने आते हैं। करीब पाँच वर्ष पूर्व मैं एक बार अपने प्रिय मित्र श्री गिरधरलाल कोटक के साथ यात्रा कर रहा था। मध्याह्न भोजन का वक्त था। रास्ते में हमने अपनी कार रोकी और हम दो-चार झोपड़े में गये। पहले पहल जिस झोपड़ी में हम गये, उसमें गायद खाने के लिए अनाज के लाले पड़े थे और दूसरे घर में रोटियों के लिए एक औरत से तीन-चार बच्चे लिपटे हुए थे। दिन का भोजन बनाना शुरू करती इससे पहले वह घर में मालिक के लौटने का इन्तजार कर रही थी। श्री कोटक बड़े सहृदय तो हैं ही, वे आँसू न रोक सके।

ऐसा ही एक वाक्यागत जुलाई माह में सामने आया। मैं एक राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के अध्यक्ष के साथ कार में सफर कर रहा था। वे मुझ से देहाती क्षेत्रों में जो महान् परिवर्तन आये हैं उस सम्बन्ध में बात कर रहे थे। कुछ हद तक उनका दावा न्यायोचित भी था। लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसी बात थी कि उक्त अध्यक्ष समग्र चित्र से अवगत नहीं है। अतएव मैंने उनसे अगले गाँव में कार रोकने का आग्रह किया। यह भी मध्याह्न भोजन का समय ही था। सर्व प्रथम हम जिस घर में गये उसका मालिक चार एकड़ जमीन पर सिकमी खेती करता था। परिवार में छ व्यक्ति थे। वे दोपहर का भोजन कर चुके थे और शाम के लिए थोड़ा-बहुत बचा कर रख दिया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा बारबार पूछताछ और करीब १० मिनट तक छानबीन करने के बाद पता लगा कि उनके घर में छ. सेर अनाज भी नहीं था। फिर हम एक दूसरे घर में गए। उस घर का मालिक भी काश्तकार था और उसके पास छ एकड़ भूमि थी। उसने भी

वैसी ही कहानी सुनायी। उसे वर्ष में तीन-चार महीने उधार पर काम चलाना पड़ता था और ब्याज की दर थी २५ प्रति शत प्रति माह। हम तीसरे घर में गये और वहाँ भी वैसी ही कहानी सुनने को मिली। ये हैं भारत के भूमिहीन श्रमिक जो हमारी ग्रामीण कृषक जन-संख्या के १७ प्रति शत हैं और ज्यो-ज्यो हमारे छोटे-छोटे भूमिधारियों के परिवारों में विभाजन होता है, प्रत्येक दशक के साथ इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। भारत में खेती योग्य जो खेत हैं, उनके ५७ प्रति शत खेत पाँच-पाँच एकड़ से छोटे हैं। समय बीतने पर वे भी भारत के भूमिहीन श्रमिकों की श्रेणी में आ जायेंगे।

अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष

अनुसूचित जातियों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है। जो व्यक्ति साफ-सफाई-खासकर छोटे-छोटे शहरों में—का काम करते हैं वे अपना अस्तित्व मात्र बनाये रखने के लिए भी बड़े कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। शेष व्यक्ति जो गाँवों में रहते हैं, उनकी हालत वहाँ के भूमिहीन मजदूरों जैसी ही है। जो कष्टमय जीवन परिगणित जन-जातियों को बिताना पड़ रहा है, उसका वर्णन अनुसूचित क्षेत्र और परिगणित जन-जाति आयोग के प्रतिवेदन में किया गया है, जिसकी यहाँ पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं। नगरों में जो गन्दी बस्तियाँ हैं, उनमें रहनेवालों की जो, फटेहाल वाली स्थिति है, उसका चित्र किसी से छिपा नहीं है। भारत के बड़े-बड़े शहरों-नगरों में 'फुट-पाथ' पर कितने व्यक्ति रहते हैं इस सम्बन्ध में आकड़े प्रस्तुत करना आसान नहीं है।

किसी देश में जो असमानताएँ हो, उन्हें राष्ट्र जीवन के सामाजिक तथा आर्थिक सन्दर्भ में मापना पड़ता है। मैंने सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं पर इतना विस्तृत विचार स्थिति की गम्भीरता व्यक्त करने के लिए ही किया है। भारत में जो असमानताएँ हैं, उन पर केवल आर्थिक रूप में ही प्रकाश नहीं डाला जा सकता। साधन-स्रोत-विहीन भारतीय आधे भूखे-नगरे रहते हैं। वे देश की जन-संख्या के एक-तिहाई हैं।

६

भारत में सहायक धंधे की भूमिका पर इस उक्त दृष्टि से विचार करना होगा। कोई भी अर्थशास्त्री किसी भूखे को अपनी अतृप्त भूख मिटाने के लिए दो कौर भोजन मिल जाये तो उसका मूल्य आर्थिक शब्दावली यानी रुपये-पैसे की भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। इन कौरों का अपना स्वयम् का मूल्य है। भूखे के लिए वे आधे पेट और भर पेट भोजन किये हुए व्यक्ति का अन्तर स्पष्ट करते हैं। इस सन्दर्भ में अर्थ-शास्त्रीय दृष्टि से विचार करना उस भूखे आदमी के 'कौरों' का मजाक उड़ाना है। कोई भी आर्थिक सिद्धान्त अभी तक यह नहीं बता सका है कि क्षुधाग्रस्त अथवा किसी तरह से अपना अस्तित्व बनाये रखनेवाली जनता के सामने किसी रक्त-क्रांति का क्या मूल्य है। इसका कारण यह है कि जब आदमी के स्वयम् अस्तित्व बनाये रखने का ही प्रश्न आ खड़ा होता है तब रुपये-पैसे का विचार कोई माने नहीं रखता। भारत की ३० प्रति शत से अधिक आबादी के समक्ष आज इसी निजी अस्तित्व का सवाल है। जो सरकार अथवा अर्थशास्त्री केवल रुपये-पैसे की शब्दावली में ही दलील पेश करता है वह मानवीय प्रकृति के सिद्धान्त के विषय में अपनी अज्ञानता ही प्रकट करता है। ये सिद्धान्त अथवा नियम अर्थशास्त्रीय नियमों से भिन्न हैं।

दोहरी समस्या

अकिंचन भारतीय जनता की सहायता करने की समस्या नैतिक और राजनीतिक दोनों ही हैं—अपने खुद के प्रयासों से अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ बनाने की दृष्टि से यह नैतिक है और समाज को अपना अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ बनाने के अर्थ में राजनीतिक। खादी और ग्रामोद्योगों की प्रासंगिकता यानी उनका स्थान भारत में अवस्थित इस नैतिक और राजनीतिक संघर्ष के सन्दर्भ या प्रसंग में ही समझना पड़ेगा। हमारे अपने देश में असमानता का उन्मूलन करने का संघर्ष हमारी बहुत बड़ी गरीब आबादी के लिए अपना अस्तित्व बनाये रखने का संघर्ष है। मात्र आर्थिक असमानताएँ समाप्त

करने अथवा केवल धन और शक्ति के सकेन्द्रण से बचने के सघर्ष से यह हमेशा ही अधिक गम्भीर है।

ग्रामोद्योग और पशु-पालन एक तरह से कृषि अर्थ-व्यवस्था की दो शाखाएँ हैं। वे भूमि की कमी पूरित करते हैं। वे खेती पर दिन प्रति दिन बढ़नेवाले भारी बोझ के कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में जो असंतुलन है, उसे कम करते हैं। वे ग्रामीणों को अपना अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ बनाते हैं। यथा सम्भव न्यूनतम पूँजी विनियोजन के साथ वे धंधे भी सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ वे प्रविधि तथा उत्पादन में व्यवहृत उपकरणों और तौर-तरीकों में सुधार करने के अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। धीरे-धीरे सुस्थिर गति से नव अभिक्रम का निर्माण करने तथा सृजनशीलता को बढ़ावा देने में भी वे सहायक होते हैं। निर्भरता और नैराश्य की भावना को वे मिटाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे सम्भाव्य हिंसात्मक कार्य-

वाहियों के विरुद्ध एक तरह से दिवाल खड़ी करते हैं, जो निराशापूर्ण अवस्थाओं के फलस्वरूप कभी भी पैदा हो सकती है। जिस खर्च पर खादी और ग्रामोद्योग सर्वसाधारण जनता के खाली समय को उत्पादनशील कामों में लगा पाये हैं, उतने कम व्यय पर अन्य कोई भी राष्ट्रीय गतिविधि वैसा करने में समर्थ नहीं हुई है। इस प्रकार सरकार जो आर्थिक मदद देती है, उससे वह न केवल व्यक्तियों की सहायता करती है, बल्कि सामाजिक कर्तव्य भी पूरा करती है। खादी व ग्रामोद्योगी उत्पादनों का ग्राहक अपेक्षाकृत थोड़ा-बहुत अधिक मूल्य चुका कर न केवल किसी व्यक्तिगत परिवार को जिन्दा रखने में, बल्कि राष्ट्र का अस्तित्व बनाये रखने में भी योगदान देता है।

बम्बई • ११ सितम्बर १९६३

आर्थिक समानता अहिंसात्मक स्वाधीनता की कुंजी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने का अर्थ पूँजी और श्रम के शाश्वत सघर्ष को मिटा देना है। इसका अर्थ यह है कि एक तरफ जिन मुठ्ठीभर धनवानों के हाथ में राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इकट्ठी हो गयी है उनका स्तर घटाया जाय और दूसरी ओर करोड़ों भूखे-नगरे लोगों का स्तर बढ़ाया जाय। जब तक धनवानों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच की चौड़ी खाई बनी हुई है तब तक स्पष्ट है कि कोई अहिंसक शासन प्रणाली कायम नहीं हो सकती। नयी दिल्ली के महलो और गरीबों तथा श्रमिक वर्ग की झोपड़ियों का अन्तर स्वतंत्र भारत में एक दिन भी नहीं टिक सकता, जिसमें कि गरीबों को भी वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जोकि धनवानों को। यदि धन का तथा धन से मिलनेवाले अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया जाता और उनका सर्वसाधारण की भलाई के लिए उपयोग नहीं किया जाता तो एक दिन हिंसक और खूनी क्रांति होकर रहेगी। मेरे सरक्षकता के सिद्धान्त की खूब खिल्ली उड़ायी गयी है, फिर भी मैं उस पर कायम हूँ। सच तो यह है कि उसे सिद्ध करना कठिन है। अहिंसा की भी यही बात है। परन्तु हमलोगों ने सन् १९२० में इस पर पहल करने का निर्णय लिया।

—महात्मा गांधी

आयोजन का गांधीवादी दृष्टिकोण*

वैकुण्ठ ल. मेहता

देश में आयोजन की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए गांधीजी के अनुसार एक ही कसौटी है। कि वह किस हद तक अधिकाधिक लोगों को काम करने का अविकार दिलवाने और भोजन, वस्त्र, शुद्ध-पच्छ जल, आवास आदि सुविधाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में सफल हुआ है। विकास कार्यक्रमों का वास्तविक फल भी इसी दृष्टि से होना चाहिए।

राष्ट्रीय आयोजन के स्वरूप अथवा पंच वर्षीय योजनाओं के उद्देश्य और कार्यक्रमों पर गांधीजी की दृष्टि से परीक्षण करना इस लेख का अभिप्राय नहीं है। ऐसा लेख निरर्थक है, और फिर, मेरे लिए तो ऐसा करना दुस्साहस ही होगा। परन्तु सामाजिक और आर्थिक आयोजन के प्रति गांधीजी का जो सामान्य दृष्टिकोण था, उसे ध्यान में रखना अप्रामाणिक न होगा। हिन्द स्वराज और गांधीजी के प्रारम्भिक लेखों के अतिरिक्त, कराची में १९३१ में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन के वक्त उन्होंने जो काम किया उसकी ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। चूंकि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरम्भ करने के बाद वह प्रथम अधिवेशन था, अतः राष्ट्रीय नेताओं का, जिनमें गांधीजी सबके अग्रणी थे, ध्यान भारत की भावी सामाजिक पद्धति की ओर केन्द्रित होना स्वाभाविक ही था। उनके विचार, जिनका गांधीजी ने न सिर्फ समर्थन, बल्कि प्रतिपादन भी किया था, राष्ट्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रसिद्ध कराची कांग्रेस प्रस्ताव में अंकित है। अतः गांधीजी राष्ट्र के विकासार्थ योजना बनाने से विमुख नहीं थे। कांग्रेस ने जब सन् १९३५ के 'गवर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट' के अन्तर्गत चुनावों में भाग लिया तथा उसके प्रतिनिधियों ने १९३७ में अविकाश प्रांतों में अपनी सरकारें बनायीं, तब गांधीजी

की सम्मति में कराची प्रस्ताव राष्ट्रीय मार्ग ही माना गया।

कांग्रेस मंत्रियों के कार्य-भार सम्हाल देने के लिए बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नेनाजी गुभाष काद साग ने १९३९ के आरम्भ में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया। नेनाजी के एक सदस्य प्रोफेसर जे सी कुमारस्वामी भी थे। नेनाजी कुटीरोद्योग समिति के अध्यक्ष श्री गनीश नन्द साग थे। ये-और दोनों ही गांधीजी के निरुद्ध मन्त्रियों थे। उसी समय श्री एम विवेकशङ्करा लिखित इकनॉमिक प्लानिंग फॉर इण्डिया प्रकाशित हुई। जिस एकाग्रता और उत्साह में मुविन्यात अभियान-राजसमर्पण ने उक्त पुस्तक तैयार की थी, जो कि उस विषय पर प्रथम पुस्तक थी। गांधीजी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, परन्तु उन्होंने उस बात पर आपत्ति उठायी कि भारतीय आयाजन का केन्द्र तीव्र सघन औद्योगीकरण है। उन्होंने उस प्रकार के औद्योगीकरण के संप्रतीकरण का विशेष रूप से विरोध किया, जो कि अस्व-स्वयं निर्धार करने की बुनियाद डालने है।

यह बात महत्वपूर्ण है कि जबकि राष्ट्रीय आयाजन समिति राष्ट्रीय विकास के विविध पक्षों में विकास योजना बनाने में व्यस्त थी गांधीजी ने देश के समस्त गरीब और अज्ञान पर आधारी अपने ध्यान में रखा कि विकास का पक्ष अत्यंत अस्व-स्वयं निर्धार है। विकास का अर्थ है आयाजन का स्थापना करना। विकास का अर्थ है आयाजन का स्थापना करना।

* गोसांसांक १९६३ में प्रकाशित। नारायण आर्या ने १६ जुलाई १९६३ को श्री गांधी के शरीर पर आयाजन का

परन्तु आर्थिक समानता अहिंसक तरीके से लानी थी, उन्हें इस बात का विश्वास था कि हिंसा के जरिये सामाजिक कानि लाने का कोई भी प्रयत्न वैसी शक्तियों को विमुक्त कर देगा जिनसे स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का सामाजिक मूल्य ही, जो कि भारत को बहुत ही पसन्द है, सकट में पड़ जायगा। रचनात्मक कार्यक्रम का मार्ग अपनाता जनतंत्र की जड़े जमाने के लिए सुनिश्चित तरीका है। वे जोर दिया करते थे कि चूँकि हमारी अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है, अतः उसे तथा सबसे निचली श्रेणी के लोगों अर्थात् हरिजनों के कल्याण कार्य को सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम के अन्य अंगों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूरदृष्टा, पद्धति-मग्न और व्यवहार शल होने की वजह से गांधीजी जो करना चाहते थे, हमेशा उसकी योजना बना लिया करते थे।

आयोजन के उद्देश्य

यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में आयोजन युग भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थापित भारतीय गणतंत्र के उद्घाटन के साथ आरम्भ हुआ है। संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के अनुरूप राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धांतों ने देश की सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वह उन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए देश के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु योजना बनाये। यह समझा गया कि औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था से मुक्त हुए देश के लिए—जिसके कुछ विभाग अल्प विकसित हैं तथा ग्रामीण विभाग निश्चल—सावधानी-पूर्वक सुनियोजित आयोजन के अभाव में प्रगति करना असम्भव-सा है। राष्ट्रीय आयोजन समिति ने योजना आयोग की स्थापना के दस वर्ष पूर्व ही उद्देश्यों की व्याख्या की थी—जिन्हें यदि गांधीजी होते तो उनकी स्वीकृति मिल सकती थी—“हमारे आयोजन की पृष्ठ-भूमि अथवा मूल परिपूर्ण लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है, जिससे समतावादी समाज का निर्माण हो, जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने तथा

आत्मपूर्ति का समान अवसर प्राप्त हो व प्रत्येक सदस्य को सभ्य ढंग के जीवन-स्तर के लिए पर्याप्त न्यूनतम निश्चित ही मिले ताकि यह समान अवसर की प्राप्ति वास्तविकता का रूप धारण कर सके।” द्वितीय और तृतीय योजना के प्रतिवेदन में उद्देश्यों की और भी विस्तृत व्याख्या की गयी है तथा उन्हें निश्चित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तृतीय पंच वर्षीय योजना में प्रथम वाक्य है “भारत के विकास का मूल उद्देश्य निश्चय ही भारतीय जनता को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना होना चाहिए।”

साधन को साध्य समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए। भारी उद्योगों का विकास, इस्पात का उत्पादन, तेल-स्रोतों का विस्तार, विद्युत उत्पादन, ये सब साध्य प्राप्ति के उपकरण हैं। यदि उन करोड़ों लोगों के जीवन को पूर्ण बनाना है, जिनका १२ वर्ष के आयोजन के पश्चात् भी कठिनाई से गुजर-बसर हो पाता है, तो प्रगति आकने के माप कुछ और ही हैं। औद्योगीकरण और शक्ति तो सामान्य लोगों के जीवन को पूर्ण बनाने हेतु स्रोत प्राप्त करने के साधन हैं। जैसा कि पूना में १९६१ में अखिल भारत सर्व सेवा सघ और ‘गोखले इस्टीमेट ऑफ पोलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स’ के संयुक्त तत्वावधान में हुई गोष्ठी में जोर दिया गया था कि सर्वोच्च प्राथमिकता हर काम चाहनेवाले व्यक्ति को रोजगार देने के उद्देश्य को दी जानी चाहिए, जिससे कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा न्यूनतम भौतिक सुख की प्राप्ति कर सके। गांधीजी के सर्वोदय समाज से यह विचार मेल खाता है।

कृषि समस्याएँ

इसका अर्थ यह है कि योजना ग्रामोन्मुखी होनी चाहिए। गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के समग्र विकास को सर्वोपरि स्थान दिया गया था। यह सच है कि कृषि उद्योग के पुनर्गठनार्थ गांधीजी के पास कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं था, परन्तु अपने रचनात्मक कार्यक्रम में उन्होंने

कृषि में सुधरे तरीके अपनाने का जोरदार आग्रह किया और कहा कि इसके विकास के लिए जिन लोगों के पास छोटे खेत हैं तथा जो आवश्यक साधन प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें सहकारी सगठन में आबद्ध हो जाने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। सहकारी खेती का आग्रह उन्होंने वर्तमान अवस्था को देखते हुए आर्थिक वचन के साधन के रूप में किया। सहकारी सगठन का विचार उन्होंने गोपालन, गोसंवर्द्धन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किया। जनता के प्रति जिम्मेदार सरकार के अभाव में उन्होंने भू-स्वामित्व के प्रश्न पर अधिक विचार नहीं किया। आज की परिवर्तित अवस्था में आचार्य विनोबा भावे इस समस्या का हल हृदय परिवर्तन, अधिकतम अहिंसा और न्यूनतम राजकीय सहयोग पर आधारित कार्यक्रम के जरिये करने की कोशिश कर रहे हैं।

तृतीय पंच वर्षीय योजना के उद्देश्यों में यद्यपि कृषि के विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है, उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु निर्यातीय कृषि सामग्रियों के उत्पादन पर जो अधिक बल दिया गया है, वह कुछ असंगत लगता है। निश्चय ही हम खेतों में अधिक पैदावार करना चाहते हैं, जिसमें कुल कृषि उत्पादन बढ़े, ताकि अन्न के मामले में हम स्वात्मन्वी बन जायें। तथापि, इससे भी अधिक स्वागतार्ह है वे उपाय जिनसे कृषि से होनेवाली आय में वृद्धि के लिए उत्पादन स्तर ऊँचा उठे और कृषि तथा शहरी उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य तथा माध्यमिक या तीसरी श्रेणी की सेवाओं से होनेवाली आय के बीच जो महान अन्तर है वह कम हो।

स्थानीय स्रोतों पर बल

विभिन्न कृषि कार्यों में यात्रीकरण अपनाने अथवा फमलो के लिए उर्वरकों का उपयोग करने में ही कृषि में सुधार नहीं हो जायगा। ये दोनों ही उपयोगी हैं, परन्तु जैसा कि गांधीजी ने हमें यह आग्रह रखा कि कृत्रिम राधानों को अपनाने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना

चाहिए कि उपलब्ध साधन-स्रोतों का पूर्ण उपयोग होता है। यदि किसी कार्य को करने के लिए जन और बैल शक्ति उपलब्ध है तो उसके बदले यांत्रिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह उत्पादन-स्तर बढ़ाने के लिए स्थानीय खाद-स्रोतों का उचित आरक्षण और पूर्ण उपयोग करने के बाद ही उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि कम परिमाण में उपलब्ध है तथा महँगे भी। समूचे गाँव के लिए खाद-स्रोत का आरक्षण प्रत्येक ग्राम आयोजन का एक अत्यावश्यक भाग होना चाहिए—जैसे कि भू-आरक्षण स्थानीय श्रम से किया जाता है—और लघु-सिंचाई कार्यों के जरिये जल-स्रोतों का आरक्षण भी किया जाना चाहिए। पशु-पालन से प्राप्त होनेवाले धन को मृत पशुओं के शव के हर भाग का पूर्ण उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है। पशु-शव सम्प्राप्ति कार्यक्रम से जो लोग शवच्छेदन, चर्मशोधन तथा अन्य सह-प्रगोधन कार्यों में लगे हैं, उनका सामाजिक स्थान उन्नत होगा और आय-स्तर भी बढ़ेगा।

दोहरी हानि

गांधीजी के विचार से ग्रामीण निश्चलता और फल-स्वरूप गाँवों की घोर गरीबी के लिए मुख्य जिम्मेदार है—ग्रामोद्योगों का ह्रास। वे प्रायः कहा करते थे कि इससे गाँव को दोहरी आर्थिक हानि होती है। ग्रामीण लोग विभिन्न पूरक वधों तथा सहायक अथवा मुख्य उद्योगों में उत्पादन कर—जिसकी गाँवों तथा शहरों दोनों ही जगह माँग थी—जो आय करते थे, वह बढ़ हो गयी। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए भी उन्हें अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देशी-विदेशी चीजें खरीदने में खर्च करना पड़ता था, जब कि वे उन वस्तुओं का उत्पादन स्वयं ही कर सकते थे और कम पैसों में अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते थे। गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में इन उद्योग-वधों की पुनर्स्थापना का प्रमुख स्थान था।

अतः हमारी अर्थ-व्यवस्था में कुटीरोद्योगों के महत्व का समझते हुए उनके विकासार्थ प्रथम पंच वर्षीय

योजना में प्रावधान रखा गया। द्वितीय योजना में मोटे तौर पर इस बात को स्वीकार किया गया कि सर्व साधारण की दैनिक उपभोक्ता सामग्रियों की आवश्यकता अधिकाधिक ग्रामीण और अन्य कुटीरोद्योगों के जरिये ही पूरी करने की कोशिश की जानी चाहिए। यह स्वीकार किया गया कि सरकार ऐसी नीति अपनाये कि वह इन उद्योगों को सहायता दे तथा संगठित भारी उद्योगों के उत्पादनों की स्पर्धा में संरक्षण प्रदान करे। यद्यपि इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि सर्व साधारण माग की हर तरह की उपभोक्ता सामग्रियों की बढ़ते परिमाण में पूर्ति ग्रामीण और कुटीर उद्योगों द्वारा की जा रही है, तथापि गत १२ वर्ष के आयोजन में यह बात तो स्पष्ट दिखाई दी है कि इन उद्योगों के जरिये लोगों को काफी सख्या में रोजगारी मिली है।

ग्रामीण औद्योगीकरण आयोग

समग्र अर्थ-व्यवस्था पर स्पष्टतः इस कार्यक्रम का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राप्त सफलता की समीक्षा करते हुए १९६१ के सर्वोदय सम्मेलन में श्री जयप्रकाश नारायण ने आग्रह किया था कि ग्रामीण-अर्थ-व्यवस्था के वैविध्यीकरण की समस्या पर अधिक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया जाय और ऐसा परम्परागत उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों को—न सिर्फ देहाती क्षेत्र की बल्कि शहरी क्षेत्रों की भी नयी उपभोक्ता और उत्पादक सामग्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए—आरम्भ करके किया जा सकता है। ये उद्योग बहुत-कुछ स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्चे माल—कृषिक तथा अन्य—पर निर्भर कर सकते हैं। तथापि, अपने क्षेत्र के बाहर से कच्चा माल मँगाने पर किसी तरह का प्रति-बन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। मुख्य ध्येय गाव के अतिरिक्त श्रमिकों को यथा सम्भव उनके घर या पास-पड़ोस में रोजगारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त किस्म का कार्य देना होना चाहिए।

फिर, नये अथवा पुराने उद्योगों में भी उन्नत तकनीकों के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, बशर्ते

कि इन पद्धतियों अथवा उपकरणों के इस्तेमाल से काम पर लगे श्रमिकों का विस्थापन न हो अथवा शोषण को प्रश्रय न मिले। इस तरह के विस्तृत और प्राणवान कार्यक्रम का आरम्भ करने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण ने ग्रामीण औद्योगीकरण आयोग की स्थापना का आग्रह किया। ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति की स्थापना तथा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आयोजन समिति के प्रति जिम्मेदार किसी एक संस्था के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों के सघन विकासार्थ योजना-बद्ध यानी अनुक्रमिक कार्यक्रम स्वीकृत कर योजना आयोग ने इस माग के मूल की पूर्ति कर दी है।

मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

यह गैर कृषि उत्पादनों के विकेन्द्रीकरण का कार्यक्रम है, जिसमें उत्पादन केन्द्र गाँव-गाँव में फैले रहेंगे, ग्रामीण ही उनके मालिक होंगे और वे ही उनका संचालन विभिन्न स्तरों पर अपने पचायत माध्यमों अथवा सहकारी समितियों के जरिये करेंगे। लेकिन जैसा कि गांधीजी ने ममझा था, कुछ उत्पादन ऐसे हैं जिनका संचालन व नियंत्रण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में किसी केन्द्रीय अधिकारी के हाथ में रहना चाहिए। जिन्हे हम आज भारी उद्योग कहते हैं, उन्हें ही उन्होंने मूल उद्योग कहा था। इनकी आवश्यकता उत्पादक माल देने तथा विद्युत् पैदा करने के लिए है, जो कि आधुनिक समाज की आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु हमारी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत तथा प्राणवान बनाने के लिए परमाश्यक है। यह गांधीजी का एक आधारभूत सिद्धांत था कि इस तरह के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए अर्थात् उन्हें सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में चलाया जाना चाहिए। अधिकारों के केन्द्रीकरण होने से नौकरशाही की अवस्था पैदा न हो और न मालिक-नौकर का सवाल पैदा हो, इसके लिए गांधीजी यही उपाय बताते कि श्रमिक का स्थान सहयोगी और भागीदार का होना चाहिए।

चूँकि सर्वोदय का अर्थ है सबका भला, जो कि अधिकाधिक लोगों के अधिकाधिक भले से अलग है, अतः

गांधीजी ने निजी तौर पर अथवा सिडिकेट या निगमों द्वारा चलायी जा रही व्यापारिक सस्थाओं को निर्मूल करने की कल्पना नहीं की। परन्तु उन्होंने इनके अधीक्षकों से आग्रह किया कि वे श्रमिकों को कार्य-नियमों तथा मुनाफे में अपना भागीदार व सहयोगी दोनों ही समझे। जबकि उन्होंने इन सस्थाओं के अधीक्षकों के उद्यम, कुशाग्रता और योग्यता को मूल्यवान माना, तो उन्हें उन्होंने जनता का न्यासी भी कहा। उन्हें अपने कला-कौशल का उपयोग सस्था के लिए जन-सेवी के रूप में करना चाहिए। इसके लिए उन सस्थाओं के—जिनको अभी निजी अथवा गैर-सरकारी विभाग कहा जाता है—अधीक्षकों के हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रत्यासिता के विचार को ऐच्छिक रूप से नहीं अपनाये जाने पर इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाज को कानूनी कार्यवाही करनी होगी।

प्रगति का मूल्यांकन

आयोजन में गांधीजी के आदर्श तथा सामाजिक मूल्य जिस हद तक समाहित हैं, उस हद तक यह दावा किया जा सकता है कि यह उस दिशा में प्रगति कर रहा है जिस दिशा में स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत की

प्रगति की कामना गांधीजी करते थे। परन्तु यदि हम भव्य के आकर्षण में बह गये, यदि हम गति को जबरदस्ती आगे ढकेलने की कोशिश करते हैं, यदि हम औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की विकास पद्धति की नकल करने का प्रयत्न करते हैं, यदि हम बेकारी और अर्ध-बेकारी को देश में जड़ जमाने देते हैं और यदि हम आय तथा धन में असमानता बढ़ने देते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि आयोजन अपने उद्देश्य में असफल रहा है, फिर चाहे समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर जो भी रही हो और इस्पात के उत्पादन, विद्युत उत्पादन, तेल, गैस और कोयला-स्रोतों की प्राप्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो अथवा रेडियो और टेलीफोन जैसी उपभोक्ता सामग्रियों में प्रति व्यक्ति खपत कितनी भी क्यों न बढ़ी हो। न सिर्फ गांधीजी, बल्कि जो प्रगति का मूल्यांकन एक अच्छे जीवन से करते हैं, उनके अनुसार एक मात्र कसौटी यह है कि आयोजन किस हद तक बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त भोजन, अच्छे वस्त्र, शुद्ध-स्वच्छ जल, आवास, साक्षरता, स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण और इन सबके भी ऊपर अपने निर्वाह के लिए काम करने का अधिकार देने में सफलता प्राप्त करता है।

पूना २ अगस्त १९६१

जिन व्यक्तियों की सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति हो उनमें ये तीन गुण होने चाहिए—
(१) सबसे पहले निर्धारित सविधान में निष्ठा; (२) सर्वोत्तम प्रशासकीय क्षमता, (३) हर प्रकार के शासन के योग्य गुण और न्याय-परायणता; क्योंकि जो न्यायपूर्ण है, यदि वह सभी शासनों में समान न हो तो न्याय का स्तर भी बदलना ही चाहिए।

—अरस्तू पॉलिटिकस

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के चन्द पहलू

मोरारजी देसाई

भारत में गरीबी का उन्मूलन करना कोई सहज काम नहीं है। कृषि, विकास का मर्मस्थल है। उसे उत्पादनशील बनाना पड़ेगा। दस्तकारियों, कुटीर तथा अन्य उद्योगों के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ना होगा। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जनता को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व स्वयम् उठाना पड़ेगा। ग्रामीण भारत का भावी चित्र ऐसा होना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से वह समृद्ध हो और ग्रामीण लोकतांत्रिक दृष्टि से काम में हाथ बटाये।

भारत में आयोजित आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम एक दशक से भी कुछ पहले प्रारम्भ हुआ था। आज हम तीसरी पंच वर्षीय योजना के मध्य से गुजर रहे हैं। हमारी समस्त योजनाओं के पीछे भविष्य की एक ऐसी कल्पना है कि भारत निर्धनता के अभिशाप से मुक्त होगा और देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने हेतु अवसर प्राप्त होंगे। इस कल्पना को साकार रूप देने हेतु हम स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन के समय से ही प्रयत्नशील रहे हैं। जब तक हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता के कोई माने नहीं होते। इस आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ही तो देश ने सोच-विचार कर वर्षों की आर्थिक गतिहीनता को तिलाजलि दी और विकास के लम्बे मार्ग पर प्रथम चरण रखा है।

निर्धनता की समाप्ति

देश के ४४ करोड़ से भी अधिक लोगों को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध कराना कोई मामूली कार्य नहीं है। यह एक बड़ा भारी काम है, और इसे पूरा करने में अनेक वर्ष लग जायेंगे। निर्धनता की समाप्ति कोई चुटकी भर में कर लेनेवाला सहज काम नहीं है। यह काम कतिपय व्यक्तियों द्वारा—चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों—एक-दो छोटे-मोटे

कार्य करने से पूर्ण नहीं हो सकता। देश की अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक अंग—खेत, कारखाने, खाने और वन—के उत्पादन में वृद्धि होनी ही चाहिए। अर्थ-व्यवस्था के ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही पहलुओं में परिवर्तन तथा विकास होना ही चाहिए।

भारत के विशाल जनसमूह का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के महान कार्य में स्वयम् ग्रामीण भारत की ही अनेक कठिन समस्याएँ हैं। भारत मूलतः ग्रामीण है और काफी समय तक ऐसा रहेगा। इसकी लगभग ८० प्रति शत आबादी गाँवों में रहती है। इस गाँवों के विकास के बिना भारत का विकास अपूर्ण और अवास्तविक अर्थात् कृत्रिम या दिखावटी ही रहेगा। वस्तुतः देश की गरीबी की जड़ें इसके गाँवों में निहित हैं। अतः ग्रामीणों की अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने तथा बेहतर जीवन बनाने के प्रयत्न में सहायता करना ही हमारा तात्कालिक, सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य है। ग्राम-समृद्धि वह आधार है जिस पर ही देश के आर्थिक विकास की इमारत खड़ी करने की आवश्यकता है।

उत्पादन वृद्धि के लिए उपाय

गाँवों में हर आठ में से सात व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं और वह उनका मुख्य

पेशा है। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है, जबकि अमेरिका में कृषि का योगदान ९ प्रति शत और जापान में १८ प्रति शत है। कृषि के आधुनिकीकरण और विकास में ही ग्राम-समृद्धि अथवा राष्ट्र की समृद्धि भी निहित है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में हमने कृषि को सर्वोपरि प्रमुखता दी है और सच तो यह है कि आगामी पन्द्रह वर्षों में भी इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जबसे योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्रारम्भ हुआ है, भारत का कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, परन्तु देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वृद्धि की यह गति अब भी बहुत धीमी है। भारत ससार के उन देशों में है जहाँ प्रति एकड़ उत्पादन न्यूनतम है। प्रति एकड़ अधिक उत्पादन करके कृषि-उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने की सम्भाव्यता हमारे लिए एक चुनौती है और साथ ही साथ कृषि उद्योग के लिए एक गर्व की बात भी। सिचाई—जोकि कृषि का प्राण है—की सुविधा, उर्वरक, उत्तम बीज और खेती-बाड़ी के उन्नत उपकरण, और इन समुन्नत उपकरणों का उपयोग करने के लिए सुशिक्षित तथा उद्यमशील किसान हो तो मुझे विश्वास है कि कृषि-उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि सम्भव है। वस्तुतः हमारे समस्त कृषि कार्यक्रमों का ध्येय, ये सब चीजें शीघ्र और व्यापक रूप से प्रदान करना है।

मर्मस्थल

कृषि उद्योग ससार के अविकाश विकासोन्मुख देशों का 'रावण की नाभि' के समान एक मर्मस्थल है। किसी भी प्रकार के कृषि सगठन या व्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने की समस्त समस्याओं में अधिकतम कृषि-उत्पादन सुनिश्चित करना सबसे कठिन समस्या सिद्ध हुई है। ग्रामीण समस्याओं के अत्यधिक महत्वपूर्ण एवम् कठिन होने के कारण देश में शांतिपूर्ण लोकतन्त्रात्मक प्रणाली से आर्थिक परिवर्तन लाने के इस सघर्ष की विजय या पराजय ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगी। लोगों को धैर्यपूर्वक समझा कर प्रेरित करने और अधिक विस्तार सेवाओं,

खेती की आवश्यक चीजों की अधिक पूर्ति, उधार तथा बिक्री सुविधाओं, प्रभावकारी भूमि-सुधार और कृषि-उत्पादन के उचित मूल्य के रूप में सक्रिय सहायता देने के सफल परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। सिचाई के साधनों में निरन्तर वृद्धि की जा रही है और अधिकाधिक किसान पानी से भरे हुए खेतों में बोआई करने (वेट फार्मिंग) के तौर-तरीके सीख रहे हैं। वस्तुतः भारत की खेती योग्य समस्त भूमि के आधे हिस्से यानी १७ करोड़ ५० लाख एकड़ में सिचाई सुविधाएँ प्रदान करने का विचार है, जबकि फिरोहाल सात करोड़ एकड़ भूमि में ही सिचाई होती है। इससे भारत में कृषि को वर्षा पर निर्भर रहने से मुक्ति दिलाने में बहुत सहायता मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उद्योग

कृषि-उत्पादन बढ़ाना एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा, और जिसके लिए धैर्य, कुशल आयोजन तथा सगठन की आवश्यकता है। इसे उर्वरकों, सुधरे उपकरणों की पूर्ति और अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री के लिए औद्योगिक क्षेत्र की ओर से अधिकाधिक मदद की आवश्यकता है। देश में आर्थिक विकास की समग्र योजना के लिए कृषि का महत्व इतना बड़ा है और ग्राम-समृद्धि से इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि मौजूदा और भविष्य की योजनाओं में इसे अधिक उत्पादक तथा लाभप्रद बनाने के लिए बड़े प्रयास करने ही चाहिए एवम् किये जायेंगे।

अधिक उत्पादनशील कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को कुछ उद्योगों की भी आवश्यकता है, ताकि वहाँ के ७ करोड़ ४० लाख परिवार शहरो तथा नगरों में रहनेवाले परिवारों के साथ कदम मिला कर चल सके। अकेली उन्नत यानी फलती-फूलती कृषि से ही देश के लगभग ८० प्रति शत ग्रामवासियों को उपयुक्त आय सुनिश्चित नहीं हो सकती। और फिर, आज बहुत अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं। इस भारी

निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है और यह काम मुख्यतः उद्योगों के जरिये ही किया जा सकता है। उद्योग एक महान् आधुनिकीकारक पहलू है और नवीन विचारों के द्वार उन्मुक्त करता है। इसके प्रभाव से कृषि और समस्त ग्रामीण समाज लाभान्वित होगा। जब हम इस सदर्थ में उद्योगों की चर्चा करते हैं तो अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं। कौन-से यानी किस प्रकार के तथा कितने उद्योग ग्रामों में शुरू किये जा सकते हैं? औद्योगिक विकास की समग्र योजना के साथ इनका कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है? उद्योगों को स्थापित करने हेतु किस प्रकार के स्थल का चुनाव हमें करना है? उद्योग विकास के लिए आवश्यक वित्त कैसे प्राप्त किया जाय?

विस्फुरण आवश्यक

औद्योगिक विकास की हमारी समग्र योजनाओं में यत्रचालित बड़े उद्योगों एवम् कुटीर और दस्तकारी उद्योगों दोनों का ही अपना-अपना स्थान है। देश के आर्थिक विकास और प्रतिरक्षा दोनों के लिए आवश्यक जटिल वस्तुओं के उत्पादन हेतु हमें बड़े कारखाना उद्योगों की जरूरत है। किन्तु ग्रामीण भारत के इकतरफे पेशेवर ढाँचे में विविधता लाने के लिए दस्तकारियाँ तथा ग्रामोद्योग महत्वपूर्ण हैं। दूरदर्शी दृष्टिकोण से विचार करने पर एक सतुलित और कुशल औद्योगिक स्वरूप का विकास करना आवश्यक प्रतीत होता है। पश्चिम के औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के अनुभव से हम कतिपय शहरों में उद्योगों के केन्द्रीकरण के फल-स्वरूप उत्पन्न हानियों से परिचित हैं।

भारत में भी अभी हाल ही तक जो थोड़े-बहुत उद्योग विकसित हुए हैं, वे कुछ नगरों के आस-पास ही हुए हैं। कतिपय बड़े नगरों में इस प्रकार के केन्द्रीकरण से कुछ प्रारम्भिक लाभ हो सकते हैं, पर कुछ ही समय बाद लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा अन्य लोकसेवाओं और सुविधाओं सम्बन्धी-इनमें जल व बिजली की

सुविधाएँ भी शामिल हैं-अनेक गम्भीर समस्याएँ एवम् बुराईयों पैदा हो जाती हैं।

अतः हमें अपने उद्योगों की योजनाएँ एक ऐसे ढंग से बनानी पड़ेगी कि उनसे हम उन गम्भीर सामाजिक और आर्थिक बुराईयों से बच सकें जो प्रायः कुछ ही शहरों में उद्योगों के सकेन्द्रण से खड़ी हुआ करती हैं। इस प्रसंग में यहाँ यह जानना रुचिकर होगा कि भारत के सबसे बड़े दस शहरों में उसकी पाच प्रति शत जन-संख्या है, जबकि जापान में २० प्रति शत, इंग्लैण्ड में १८ प्रति शत और संयुक्त राज्य अमेरिका में १२ प्रति शत। लेकिन हमें जापान या ब्रिटेन की तरह जन-संख्या का भारी केन्द्रीकरण नहीं चाहिए। इसके साथ ही हम प्रत्येक गाँव को दीर्घ-स्तरीय उद्योग का केन्द्र भी नहीं बना सकते। इसलिए उद्योगों की आदर्श संरचना यह लगती है कि देश में कुछ एक-सौ उद्योग केन्द्र हों जो पूरे देश भर में अच्छी तरह फैले हों। इस प्रकार के ये केन्द्र औद्योगिक विकास के प्रतिनिधि केन्द्र होंगे। उद्योगों की ऐसी संरचना यानी स्थापना से गाँवों और शहरों के बीच जो अंतर है उसमें कमी हो सकेगी। इस प्रकार उद्योगों की प्रस्थापना के साथ-साथ हमें एक नये प्रकार के उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता है। वे न तो कुटीर एवम् दस्तकारी उद्योगों जैसे ही होंगे और न यत्र-चालित बड़े उद्योगों जैसे ही और इस प्रकार के उद्योगों में छोटे उद्योगों जैसी लोगों को काम देने की क्षमता होगी तथा बड़े उद्योगों जैसी उत्पादन-क्षमता। देश की पूर्ण एवम् अर्ध-बेकारी की गम्भीर समस्या का बहुत-कुछ समाधान इस प्रकार के उद्योगों के विकास में सफलता पर ही निर्भर है।

बचत पर जोर

हमारे ग्रामीण अथवा समूचे आर्थिक विकास का स्वरूप चाहे जो भी हो, हमें अपनी विकास योजनाओं के लिए साधन-स्रोत खोजने ही पड़ेंगे। यह कैसे हो? ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर ब्रिटेन, जर्मनी और जापान

मे औद्योगीकरण कृषि क्षेत्र से साधन-स्रोत छीन कर किया गया। भारत में हम उस अनुभव की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते। परन्तु यह आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि कम से कम खेती के विकास के लिए तो उससे साधन-स्रोतों की पूर्ति हो। विकास के लिए आवश्यक सभी वित्त की पूर्ति या तो हमारी बचत से करनी पड़ेगी या फिर किसी दूसरे की बचत से। यहाँ आकर ग्रामीण बचत अभियान, कराधान, अनिवार्य जमा योजना और स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का महत्व सामने आता है। इनमें से पहले तीन—जहाँ तक उनका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग से सम्बन्ध है—ग्रामीण क्षेत्रों में बचत निर्मित तथा सक्रिय बनाने के लिए है तो स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का ध्येय स्वर्ण जैसी अनुत्पादन चीज पर बचत को लगाने से रोकना है। मौजूदा हालत में स्वर्ण खरीदना देश का अहित करना है, क्योंकि जितना सोना आज खरीदा और बेचा जाता है वह अधिकांशतः चोरी से लाया हुआ होता है। इस प्रकार से प्राप्त सोने से देश को नुकसान और तस्कर व्यापारी को फायदा होता है।

सहकारिता, विद्युतीकरण, गोदाम तथा बिक्री सम्बन्धी सुविधाओं जैसे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के और भी अनेक पहलू हैं, जिनका विकास ग्राम-प्रधान भारत का स्वरूप बदलने के लिए किया जा रहा है। सहकारिता और विद्युतीकरण दोनों ही ग्रामीण प्रगति की गाड़ी खींचनेवाले दो बैल हैं। कृषि क्रांति के आरम्भ और संचालन तथा साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी सस्कृतियों के मध्य भारी अंतर को कम करने के लिए ये दोनों अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

त्रि-सूत्री व्यवस्था

भविष्य के ग्रामीण भारत की कल्पना केवल आर्थिक ही नहीं है। लोकतंत्र के रूप में विकास योजनाएँ बनाने तथा कार्यान्वित करने के काम में ग्रामीणों सहित हर

व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवम् सक्रिय भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना आवश्यक है। पंचायत राज ग्रामवासियों को ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए है। पंचायत राज देश के ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक व दूरगामी परिवर्तन है। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य समस्त ग्रामवासियों को ग्राम विकास योजनाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करना है। यह त्रि-सूत्री व्यवस्था है, जिसमें तीन निर्वाचित स्थानीय संस्थाएँ आती हैं—ग्राम स्तर पर पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत राज की महान सम्भाव्यताएँ इस बात में निहित हैं कि राज्य सरकारों के मार्गदर्शन व निरीक्षण में ग्राम विकास की योजनाएँ कार्यान्वित करने का अन्तिम उत्तरदायित्व अधिकाधिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिये ग्रामीणों पर पड़ता जायगा।

लोकतांत्रिक भागीदारी

यद्यपि पंचायते हमारे देश की प्राचीन संस्थाएँ हैं, पर लोक कल्याण यानी गाँव के सामान्य हित की दृष्टि से गाँवों का विकास करने का जो उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है, वह अपेक्षाकृत नया ही है। पंचायत राज के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत को नहीं तो कम से कम पंचायत समितियों को तो स्थानीय साधन-स्रोतों का पूरा उपयोग करने के लिए योजनाएँ बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय साधन-स्रोत यदि पूरे तौर पर नहीं तो कम से कम आंशिक रूप में जुटाना सीख ही जाना चाहिए। आर्थिक समृद्धि और ग्रामीण संस्थाओं में लोकतांत्रिक भागीदारी से परिपूर्ण यही तो वह ग्रामीण भारत का चित्र है, जो गांधीजी ने हमारे सामने रखा था।

नयी दिल्ली ४ सितम्बर १९९३

शैक्षणिक प्रगति तथा औद्योगीकरण

कन्दस्वामी अरुणाचलम्

योजना आयोग ने १९५१ में सगठित और सुव्यवस्थित राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों की पुन व्याख्या की, तौर-तरीके तथा विषय-सामग्री तैयार की एवं उसके लक्ष्य को नया रूप दिया। शिक्षा में शहरी मूल्यों की प्रमुखता होने की वजह से आर्थिक विकास का पलड़ा भी शहरी क्षेत्र की ओर झुका हुआ है। शैक्षणिक सुविधाओं की दृष्टि से अभाव-ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा अन्य बातों की कमी भी पायी जाती है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का विस्तृत पैमाने पर विस्तार किया जाय, तो वहां औद्योगीकरण के लिए वातावरण निर्मित करने में बहुत सहायता मिलेगी।

शिक्षा अर्थ-व्यवस्था को अनेक दृष्टियों में प्रभावित करती है। न केवल यह कौशल प्रवाह में वृद्धि करती है वरन् नयी-नयी तकनीकों की ज्ञान-प्राप्ति में सहायता भी देती है। और फिर, यह प्रगति-अवरोधक पुराने दृष्टिकोण या विचार को नष्ट करने की ओर प्रवृत्त होती है, यह ज्ञान को उत्पादन के साथ जोड़ती है। दूसरी ओर शिक्षा-पद्धति पर अर्थ-व्यवस्था की तरफ से विज्ञान के जरिये प्रतिक्रिया होती है, जिसने आज उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है तथा विद्यालयों में जिसकी अधिकाधिक शिक्षा दी जाती है। अतएव एक तरफ शिक्षा अर्थ-व्यवस्था को शक्ति-शाली बनाने में सहायक होती है, क्योंकि जन-शक्ति में यह एक प्रकार का निवेश अर्थात् विनियोजन है, जबकि दूसरी ओर यह बहुत खर्चीली बनती जा रही है। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, शिक्षा के लिए अधिक निधि दी जा सकती है। हमारी अर्थ-व्यवस्था की गति बर्मा और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों से भी धीमी है। हमारे यहाँ अभियंतों (इंजीनियरों) और वैज्ञानिकों की कमी है। हमें बहुत शीघ्र ही सैकड़ों-हजारों अपेक्षाकृत अधिक योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

अतएव शिक्षा न केवल बच्चों को सहायता देने, उनका जीवन बेहतर बनाने, जिस समाज में हम रहते हैं उसे समुन्नत करने तथा देश को अपने मार्ग में आगे

वढ़ते रहने और अन्तर्गर्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए ही महत्वपूर्ण है, वरन् यदि हम परिवर्तनशील प्राविधिक एवं वैज्ञानिक युग में अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं तो उसके लिए अर्थात् उस दृष्टि से वह परमावश्यक भी है। किन्तु मात्र शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, उसीसे काम नहीं चलेगा। महत्व उस बात का भी है कि शिक्षा कैसी और किस ढंग की है, जिस ससार में हम रहते हैं, शिक्षा उसके अनुरूप ही होनी चाहिए, उससे व्यक्ति को जीवन व परिवर्तनों के लिए तैयार होना ही चाहिए। मानव को अपना विकास करने तथा अपने को ग्रहणशील बनाने में भी शिक्षा में सहायता मिलनी ही चाहिए। और अन्त में, वह सभी तक अवश्य पहुँचनी चाहिए।

स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व

स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत में शिक्षा का उद्देश्य था—अंग्रेजी प्रशासन और सैनिक सेवाओं में काम-काज करने के लिए शिक्षित भारतीय वर्ग में से बाबू यानी क्लर्क तैयार करना। उस वक्त के 'शिक्षित वर्ग' में अधिकांशतः क्लर्क और सैनिक तथा 'मुट्ठीभर' व्यावसायिक व्यक्ति ही थे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजों के एजेण्टों के रूप में काम किया। जिन विचारों और प्रभावों ने अंग्रेजों को अपने देश में प्रेरित किया उनसे अनुप्राणित हो उक्त स्वदेशी व्यक्तियों ने भी उन्हीं गीति-रिवाजों तथा नीति का अनुसरण किया और वह भी अधिक सघनता

के साथ। लोक शिक्षा के बजाय वर्ग शिक्षा उस वक्त का एक नियम-सा, फैशन-सी बन गयी थी और अनेक मामलो में आज भी बनी हुई है। इस प्रकार की नीति का अपरिहार्य परिणाम निकला विशुद्ध साहित्यिक शिक्षा पर जोर देने की अति और वह भी विदेशी भाषा के माध्यम से। स्कूल और कालेज किसी एक स्तर के शिक्षित व्यक्ति पैदा करनेवाले कारखाने जैसे बन गये।

देश जब आजाद हुआ तब ६ से ११ वर्ष तक की आयुवाले ४० प्रति शत और ११ से १७ वर्ष तक की आयुवाले १० प्रति शत बालक ही स्कूलों में जाते थे। देश के विभिन्न भागों, भिन्न-भिन्न वर्गों और विशेष कर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था में असमानताएँ थी।

शिक्षा पद्धति के विभिन्न सोपानों पर काफी बर्बादी होती थी। प्राविधिक तथा वृत्तिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ बिल्कुल अपर्याप्त थी। प्रशिक्षण-विहीन शिक्षकों का अनुपात प्राथमिक विद्यालयों में ४१ प्रति शत और माध्यमिक विद्यालयों में ४६ प्रति शत से अधिक था। अध्यापिकाओं की बहुत कमी थी। अध्यापकों का वेतन-स्तर तथा नौकरी सम्बन्धी अवस्थाएँ सामान्यतः असन्तोषप्रद थी और किसी अंश तक निम्न शिक्षण-स्तर के लिए उत्तरदायी भी।

स्वतंत्र देश में

ऐसी अवस्था में न तो व्यक्तिगत अभिक्रम की आवश्यकता थी और न स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिलता था। नकल, पुनरावृत्ति, बिना किसी अतः अथवा अन्तर के एक ही काम की चक्की चलाते जाना (रूटीन वर्क) तब का एक परिशुद्ध नियम था। एक स्वतंत्र देश में इस प्रकार की स्थिति दीर्घ काल तक नहीं चल सकती थी। एक स्वतंत्र राष्ट्र में वहाँ के नागरिकों को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वहन करना और राष्ट्र के शासन-संचालन में अधिकार काम में लाना पड़ता है। इस प्रकार एक नयी शैक्षणिक नीति और कार्यक्रम की रचना कर उसे समग्र देश में स्वीकृत कराना था। तदनुसार १९५१ में राष्ट्रीय

योजना आयोग ने पुनः सगठित और सुव्यवस्थित राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या की, तौर-तरीके तथा विषय सामग्री तैयार की एवं उसके लक्ष्य को नया रूप दिया।

परिमाणात्मक विकास

तत्पश्चात् १९५०-५१ से १९५९-६० तक के दशक में सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जानेवाले वार्षिक व्यय में वृद्धि हुई और प्रथम वर्ष का ६५ करोड़ रुपये का व्यय अन्तिम वर्ष (१९५९-६०) में दो अरब तक पहुँच गया। कुल खर्च—जिसमें स्थानीय सस्थाओं, शुल्क तथा अन्य धर्मार्थ सस्थाओं का खर्च शामिल होता है—एक अरब चौदह करोड़ से बढ़ कर दो अरब सत्तानवे करोड़ रुपये तक पहुँचा। कुल जनसंख्या के प्रति ६ से ११ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का अनुपात प्रथम से पाचवीं कक्षा तक १९५०-५१ में मात्र ४२ प्रति शत था। यह अनुपात १९६०-६१ में बढ़ कर ६१ प्रति शत हुआ। तृतीय योजना की समाप्ति तक ७६ प्रति शत का लक्ष्यांक प्राप्त करना है। चतुर्थ योजना के अन्त तक आशा है कि स्कूल जाने लायक आयुवाले सभी बालक पढ़ने जाया करेंगे। यह सच है कि अन्य स्तरों पर भी पढ़ने के प्रातिशत्य में काफी वृद्धि हुई है, जैसे ११ से १४ वर्ष के आयु वर्ग का प्रातिशत्य १२ से बढ़ कर २८ प्रति शत हुआ, इसी प्रकार १४ से १७ वर्ष के आयु वर्ग का प्रातिशत्य ५ से १५, और १७ से २३ वर्ष वाले आयु वर्ग का प्रातिशत्य ०.९ से २.४ हो गया। किन्तु यह भी एक तथ्य है कि १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो सवैधानिक निर्देश है वह अभी तक तो एक निर्देश ही बना हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में अनिवार्य शिक्षा के लिए कानून बनाये जा चुके हैं। विद्यालयों में सघन प्रवेश के लिए योजनाएँ बनी हैं। शिक्षकों (१५ लाख) को प्रशिक्षित करने की योजनाएँ भी बनायी गयी हैं।

भारत में १९५०-५१ से १९५९-६० तक की अवधि में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह तालिका १ (पृष्ठ २२) में दी जाती है

तालिका १

भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति : १९५०-१९६०

वर्ष	मान्य विद्यालय	छात्र सख्या	शिक्षक सख्या	प्रत्यक्ष व्यय (करोड रुपये में)
१९५०-५१	२,०९,६७१	१,८२,९३,९६७	५,३७,९१८	३६ ४९
१९५५-५६	२,७८,१३५	२,२९,१९,७३४	६,९१,२४९	५३ ७३
१९५६-५७	२,८७,२९८	२,३९,२२,५६७	७,१०,१३९	५८ ४८
१९५७-५८	२,९८,२४७	२,४७,८८,२९९	७,२९,२३९	६६ ७४
१९५८-५९	३,०१,५६४	२,४३,७२,१८१	६,९५,२८०	६३ ६४
१९५९-६०	३,२०,५८६	२,५९,१८,८६४	७,३३,३८२	६९ ६३

तालिका २ माध्यमिक (सेकण्डरी) विद्यालयों के विकास और वित्तीय पहलुओं का एक विहंगम चित्र प्रस्तुत करती है।

तालिका २

भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति : १९५०-१९६०

वर्ष	विद्यालय	छात्र सख्या	शिक्षक सख्या	प्रत्यक्ष व्यय (करोड रु में)
१९५०-५१	२०,८८४	५२,३२,००९	२,१२,०००	३० ७४
१९५५-५६	३२,५६८	८५,२६,५०९	३,३८,१८८	५३ ०२
१९५६-५७	३६,२९१	५९,७९,१६४	३,७२,१८०	५८ ७३
१९५७-५८	३९,६५४	१,०६,२१,४९९	४,०६,७६८	६७ २१
१९५८-५९	५३,९२३	१,४३,४१,०४३	५,१०,३८८	८४ ३४
१९५९-६०	५७,८६३	१,५७,०६,२००	५,६१,९५९	९५ ६५

तालिका ३ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में हुई संस्थागत प्रगति का एक चित्र प्रस्तुत करती है।

तालिका ३

भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास १९५०-१९६०

वर्ष	विश्व विद्यालय	शिक्षा मंडल	अन्वेषण संस्थाएँ	विशिष्ट शिक्षा कालेज	प्राविधिक कालेजों के वृत्तिक	कला व विज्ञान कालेज	छात्र-सख्या	शिक्षक सख्या	प्रत्यक्ष व्यय (करोड रुपये में)
१९५०-५१	२७	७	१८	९२	२०८	४९८	४,०३,५१९	२४,४५३	१७ ६८
१९५५-५६	३२	११	३४	११२	३४६	७१२	६,८१,१७९	३७,८६५	२९ ७१
१९५६-५७	३३	१२	४१	१२८	३९९	७७३	७,५०,१९५	४२,१३५	३३ ५४
१९५७-५८	३८	१४	४३	१४८	४८९	८१७	८,०३,९४२	४५,२३२	३८ १०
१९५८-५९	४०	१३	४२	१६८	५४२	८७८	८,७६,३१२	५२,१८०	४३ ९२
१९५९-६०	४०	१३	४२	१७७	७२८	९४६	९,४०,४८४	५५,४९३	४७ ७१

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् प्राविधिक और वृत्तिक शिक्षा के विस्तार की जरूरत महसूस की गयी। प्राविधिक तथा वृत्तिक शिक्षा की विकास योजनाओं में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने हेतु १९४५ में प्राविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद गठित की गयी। सन् १९४७ के प्रारम्भ में युद्धोत्तर विकास कार्यक्रमों पर विचार हो रहा था। उनके लिए आवश्यक वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों का मूल्यांकन करने का कार्य वैज्ञानिक जन-शक्ति समिति (साइण्टिफिक मैन पावर कमेटी) को सौंपा गया। इस क्षेत्र में सुविधाएँ बढ़ाने के लिए प्रथम पंच वर्षीय योजना से पहले अनेक कदम उठाये गये। खडगपुर में 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी' की स्थापना, और विकास के लिए १४ प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं का चुनाव, गवेषणा प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु वृत्तिका के लिए प्रावधान तथा वैज्ञानिक एवम् प्राविधिक शिक्षा व अन्वेषण के प्रोत्साहनार्थ अन्य योजनाएँ इन सुविधाओं में शामिल थी। इस काल में और दो योजनाओं के अन्तर्गत उठाये गये कदमों के परिणाम, नीचे तालिका ४ में, १९५०-१९६० के बीच की अवधि में अभियांत्रिक तथा प्राविधिक संस्थाओं के विकास में हुई वृद्धि में परिलक्षित है।

गुणात्मक सुधार

आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का कितना भारी

महत्व है, इसकी शायद ही अतिशयोक्ति हो अर्थात् उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के ससार में अनेक देशों में आर्थिक विकास और शैक्षणिक स्तर में परिपूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे अपने देश में भी शिक्षा में शहरी मूल्यों की प्रधानता के कारण आर्थिक विकास के पलड़े का झुकाव भी शहरों की ओर ही है। देहाती क्षेत्रों में अब भी शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। आज भी वे दुख-दर्दों और भुखमरी के शिकार हैं। जहाँ-कहीं शिक्षा की दृष्टि से लोप पिछड़े हुए हैं, वहाँ अर्थ-व्यवस्था भी पिछड़ी हुई है। हमें आजाद हुए पन्द्रह वर्ष हो गये। इस अवधि में हमने अनुभव भी प्राप्त किये हैं। फिर भी, हम आज अन्धेरे में पत्थर फेंक रहे हैं और अपनी शक्ति तथा अल्प राष्ट्रीय स्रोत गँवा रहे हैं। एक ही साथ कई योजनाएँ चालू करने की पद्धति से हमारे प्रयासों की बर्बादी होती है और प्राप्त परिणाम महत्वहीन बन जाते हैं। जैसा कि विनोबाजी कहते हैं, "सभी प्रकार की शिक्षा का एकमेव उद्देश्य है कि देश के सभी नागरिक कुशल दस्तकार और स्पष्ट विचारक बन जायें। लेकिन हम इस उद्देश्य को अनेक भागों-टुकड़ों में बाँट देते हैं, जैसे शहरी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, बाल शिक्षा, घाय शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पुरुष शिक्षा, दस्तकार शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और इन सबके ऊपर आता है साक्षरता अभियान।"

विनोबाजी का मत है कि यदि हम इन सभी पहलुओं

तालिका ४

इंजीनियरिंग कालेजों और पॉलिटेक्निक्स की प्रगति १९५०-१९६०

वर्ष	स्नातक पाठ्यक्रम			डिप्लोमा पाठ्यक्रम		
	संस्थाएँ	प्रवेश क्षमता	शिक्षा प्राप्त व्यक्ति	संस्थाएँ	प्रवेश क्षमता	शिक्षा प्राप्त व्यक्ति
१९५०-५१	४९	४,१२०	२,२००	८६	५,९००	२,४८०
१९५५-५६	६५	५,८९०	४,०२०	११४	१०,४८०	४,५००
१९६०-६१	१००	१३,८६०	५,७००	१९६	२५,५७०	८,०००
१९६५-६६*	११७	१९,१४०	१२,०००	२६३	३७,३९०	१९,०००

* अनुमानित।

पर अलग-अलग रूप में विचार करेंगे तो निश्चय ही हमारी प्रगति रुक जायेगी। हर आदमी को खुश करने के लिए अल्प स्रोतों का वितरण किया जा रहा है। इसका परिणाम यह निकलता है कि ऐसी शैक्षणिक वाता को, अपेक्षाकृत उपेक्षित करना पड़ता है। जिनमें बचा नहीं जा सकता और जो तुरन्त करने योग्य हैं यदि हमारा ध्यान थोड़ा इस ओर, थोड़ा उस ओर बँट जाता है तो हमें कहीं भी वास्तविक सन्तोष नहीं मिलेगा। हमें दृढ़ता के साथ मूल प्रश्न को लेना है और इस बात पर परिपूर्ण ध्यान देना है कि उस पर उचित कार्यवाही होती है। मूल है बुनियादी तालीम। दस्तकारी भी इसमें आ जाती है, बौद्धिक विकास भी और साक्षरता भी। यह एक गतिविधि-केन्द्रित पाठ्यक्रम है, जिसमें ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया बच्चे के शारीरिक और सामाजिक वातावरण के साथ परस्पर जुड़ी हुई है। शिक्षा कतार और बुनाई, बागवानी, बड़ईगिरी, चर्म कार्य, घरेलू दस्तकारी, कुम्भकारी, प्रारम्भिक अभियांत्रिकी आदि जैसी सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से दी जाती है। यद्यपि बुनियादी शिक्षा प्रारम्भिक स्तर पर अब शिक्षा पद्धति की राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत पद्धति है, तो भी प्राथमिक विद्यालयों की सख्या में बुनियादी तालीम के मात्र २९ प्रति शत विद्यालय हैं। शेष वही 'मैकाले पद्धति' वाली किताबी शिक्षा देते हैं। तीसरी योजना के अन्त तक यह प्रातिशत्य बढ़कर ३६ हो जाने की अपेक्षा है। कहा जाता है कि इस विलम्ब का कारण है शिक्षा के लिए उपलब्ध साधन-स्रोतों की कमी। किन्तु जो मुख्य कारण सुस्पष्ट है वह यह है कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसमें और राष्ट्र के औद्योगिक विकास में जो पारस्परिक सम्बन्ध है, शैक्षणिक प्रशासकों को अभी तक उसकी प्रतीति नहीं हो पायी है। पुरानी नौकरशाही वाली प्रवृत्ति आज भी पायी जाती है। बाबूगिरी को आज भी अच्छा समझते हैं।

तथापि, बताया जाता है कि गैर बुनियादी प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा के चन्द उन महत्वपूर्ण-विषयों को प्रारम्भ किया जा रहा है, जिनके सम्बन्ध में

व्यय की बात नहीं है। अधिकारियों और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नवीनीकरण पाठ्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। जिस ढंग में कदम उठाये जा रहे हैं, उनमें यह नहीं प्रकट होता है कि शिक्षा की यह क्रांतिकारी पद्धति समझ-बूझ कर तथा हृदय से स्वीकृत की जा रही है। देश भर में इस शिक्षा पद्धति के विस्तार से ही भारत के साढ़े-पाँच लाख गाँवों में उद्योग फैलेगे। तब वे गतिविधियों के केन्द्र होंगे और देश से अल्प तथा पूर्ण बेकारी को मार भगायेगे।

सभी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण मस्थाओं को अनुक्रमिक रूप में बुनियादी ढंग की मस्थाओं में बदला जा रहा है। सत्तरह वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए माध्यमिक शिक्षा को परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। उनमें एक अनुपम परिवर्तन है बहुमुखी शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी को सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त मानव शास्त्र, विज्ञान, प्रविधि, वाणिज्य, कृषि, परिष्कृत कलाओं तथा गृह विज्ञान में से तीन विषयों का चुनाव करने की छूट है।

विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया जा रहा है। यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की ग्राम्य विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गयी हैं, तथापि चन्द ग्राम्य संस्थान खुले हैं। अधिकाधिक प्राविधिक और वृत्तिक विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं।

कृषि शिक्षा

शिक्षा पद्धति में एक दोष यह है कि कृषि स्नातकों के प्रशिक्षण और अशिक्षित कृषक जनता के बीच बहुत बड़ी खाई है। जिस वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत बहु-उद्देश्यीय उच्च विद्यालयों अथवा अलग-अलग पाठ्यक्रमों में कृषि-विषयक पाठ्यक्रम का प्रावधान है वह किसी भी व्यावहारिक उद्देश्य यानी काम के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। जहाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल व्यावहारिक

पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जा सकती है, वहाँ कृषि को बुनियादी दस्तकारी के रूप में लेकर अनेक उत्तरबुनियादी विद्यालय स्थापित करना वाछनीय होगा। इन विद्यालयों में शिक्षित-प्रशिक्षित विद्यार्थी अपने खेतों व खेती करने के तौर-तरीकों में सुधार और कृषि उत्पादन बढ़ाने में समर्थ होने चाहिए। कृषि विकास देश में विस्तृत औद्योगिक विकास करने की कुन्जी है, जान है। इसका कारण यह है कि कृषि अधिकांश उपभोक्ता सामग्री उत्पादित करनेवाले उद्योगों का आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को इस दृष्टि से मोड़ देने पर व्यक्ति को मनुष्यत्व-विहीन बनाये बिना भारत का औद्योगीकरण करना सम्भव बन सकेगा।

परिमाणात्मक दृष्टि से हमने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यदि प्राविधिक शिक्षा के द्रुत विस्तार

से हमें मात्र नकल करनेवाले और स्वचलन का अनुकरण करनेवाले बनने से बचना है तो शिक्षा के गुण एवम् उसकी उपयुक्तता पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देना चाहिए, परिष्करण की वेदी पर हमें गुण की बली नहीं चढ़ा देनी चाहिए। हम गुण के सम्बन्ध में इतने आतुर इसलिए हैं कि हम उद्योगवाद की बुराइयों से बचते हुए देश में उद्योग फैलाना चाहते हैं। औद्योगीकरण यदि आज की तरह चन्द बड़े-बड़े नगरों में ही होता है, तो ग्राम रूपी भारत के हृदय का शोषण होता रहेगा तथा अन्ततोगत्वा समूचा देश बर्बाद हो जायेगा। उपयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के द्वारा ही इससे बचा जा सकता है।

मदुराई २ अगस्त १९६३

कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य इस बात से निर्धारित किया जाये कि उसमें कितना श्रम लगा है, तो श्रमिक जितना ही अधिक सुस्त व अकुशल होगा उस वस्तु का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि उसके उत्पादन में अधिक समय लगेगा। मूल्य में श्रम का जो भाग होता है वह सयुक्त मानव श्रम होता है अर्थात् एक समान श्रमशक्ति का व्यय। समाज की सम्पूर्ण श्रम-शक्ति जो कि उस समाज द्वारा निर्मित सभी सामग्रियों में निहित होती है, मानव-श्रम-शक्ति का सयुक्त पुंज होती है, यद्यपि उस शक्ति में असंख्य व्यक्ति रूपी इकाइयों की शक्ति मिली होती है। जहाँ तक समाज की औसत श्रम-शक्ति के स्वरूप का सम्बन्ध है, इन इकाइयों में से प्रत्येक इकाई दूसरी के समान ही होती है और इसी रूप में वह घटित होती, अर्थात् उस वस्तु के उत्पादन में औसत समय ही खर्च होता है, और सामाजिक दृष्टि से जितना समय आवश्यक है उससे अधिक समय नहीं खर्च होता है। सामाजिक दृष्टि से श्रम रूपी समय वही है जो कि उत्पादन की सामान्य परिस्थितियों में कार्यकुशलता के औसत स्तर के साथ और उस समय प्रचलित गति व तीव्रता के साथ उस वस्तु के निर्माण में लगे। इंग्लैण्ड में शक्ति-चालित करघों के प्रचलन से सभवतः सूत की निश्चित मात्रा का कपड़ा बुनने के लिए आवश्यक श्रम में आधे की कमी हो गयी। वास्तव में हाथ करघे के बुनकरों को पहले जितना ही समय लगता रहा, परन्तु उनका एक घण्टे का श्रम इस परिवर्तन के बाद केवल आधे घण्टे के सामाजिक श्रम के बराबर हुआ और इस कारण उसका मूल्य पहले के मूल्य का आधा हो गया।

--कार्ल मार्क्स 'कैपिटल', खण्ड १

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग कार्यक्रम

त्रिभुवन नारायण सिंह

ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना और गाँवों में गैर खेतिहर काम-वधो का सृजन करना ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य है, लक्ष्य है। कार्यक्रम के प्रवर्तकों ने उत्पादन के उन्नत तौर-तरीके अपनाने और जहाँ शक्ति उपलब्ध हो वहाँ उसका उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ग्रामीण उद्योगों के आयोजित विकास में सफलता प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार को और भी वस्तुपरक, मोद्देश्य तथा ठोस कदम उठाने पड़ेगे।

दिल्ली में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उद्योग मंत्रियों का हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था। ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के सम्बन्ध में उक्त सम्मेलन में चन्द महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय सवालात उठाये गये थे। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर विचार हुआ उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की महत्ता का उपयुक्त मल्याकन करने, उन्हें सही रूप में पहचानने के लिए उक्त कार्यक्रम के प्रधान उद्देश्यों और मान्यताओं का कुछ विस्तृत विश्लेषण करना वाछनीय होगा।

प्रधान उद्देश्य

ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना तथा उच्च स्तरीय आय करवानेवाली उत्पादनशील गतिविधियाँ के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करना कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य यानी लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर खेतिहर वधो के लिए विस्तृत अवसर निर्मित करने की योजना है। उत्पादन के उन्नत, विकसित तौर-तरीके अथवा जिसे 'माध्यमिक प्रविधि' (इण्टरमीडिएट टेक्नालॉजी) कहा जाता है उसे न केवल कृषि उत्पादनों एवम् अन्य कच्ची सामग्री का प्रगोधन करने के लिए वरन् यात्रीकृत लघु उद्योगों के लिए भी अपनाना है। लोग उच्च उत्पादन क्षमतावाले बेहतरीन यंत्रों का संचालन कर सकें, इसके लिए उन्हें इस नये कौशल का प्रशिक्षण देने और संगठन तथा व्यवस्था कार्य के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है।

ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम की चन्द मान्यताओं को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है

मान्यताएँ

अ खेत बहुत छोटे-छोटे हैं तथा द्रुत गति से बढ़ रही आबादी के कारण वे और भी छोटे हो जायेंगे, इसलिए काफी आबादी को कृषि से हटा कर अन्यान्य वधो में लगाना आवश्यक हो गया है।

आ. एक ऐसी स्थिति में जिसमें लोग बहुत बड़ी तादाद में देहाती क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर अनवरत रूप से काम की तलाश में जाते हों, भयंकर सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, जिन्हें हो सकता है कि हल करना ही मुश्किल हो जाय।

इ यदि आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाय और लोगों को आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्हें काफी तादाद में गैर खेतिहर काम-वधो उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

ई ग्रामीण क्षेत्रों में आज काफी परिमाण में अमूल्य कच्ची सामग्री बर्बाद यानी बेकार जाती है। यदि नवीन तथा वैज्ञानिक तकनीक प्रारम्भ की जाय, तो काफी लोगों को काम मिलना चाहिए।

उ कृषि उत्पादन पर आधारित प्रगोधन उद्योगों के लिए व्यापक क्षेत्र है और यदि उनमें उपयुक्त वैज्ञानिक

तौर तरीके अपनाये जाये तो वे दीर्घ-स्तरीय इकाइयों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

शक्ति की उपलब्धि

प्रधान मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन करते वक्त आवश्यक सुविधाएँ—विशेष कर बिजली—उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पर काफी जोर दिया था। ऐसा होने से ही ग्रामीण आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को कृषि के अतिरिक्त अन्य काम-धंधे अपनाने के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं। कुछ अन्य वक्ताओं ने भी इस प्रश्न पर जोर दिया और यहाँ तक कहा कि शक्ति की उपयुक्त पूर्ति के बिना ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण का कोई विशाल कार्यक्रम चलाना सम्भव नहीं है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि निकट भविष्य में ही लगभग एक लाख गाँवों का भी विद्युतीकरण करना सम्भव प्रतीत नहीं होता तो फिर कम से कम एक लाख गाँवों तक बिजली न पहुँच जाय, क्या तब तक ग्रामीण औद्योगीकरण का समग्र कार्यक्रम त्याग देना चाहिए? मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री का मकसद यह नहीं था कि शक्ति की उपलब्धि हो तब तक के लिए ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम से नमस्कार कर लेना चाहिए। यदि ऐसा होता तो वे सम्मेलन का उद्घाटन करना स्वीकार न करते।

विभिन्न अवस्थाएँ

ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के प्रवर्तकों ने प्रारम्भ से ही उत्पादन के यात्रिक तौर-तरीके और जहाँ उपलब्ध हो वहाँ शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। जो ४६ परियोजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं उनमें से अधिकांश उन स्थानों में हैं जहाँ शक्ति उपलब्ध है, यद्यपि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ शक्ति जैसी सुविधाओं की कमी है। इस प्रकार की मिश्रित व्यवस्था इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर खेतिहर काम-धंधों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति को विभिन्न अवस्थाओं के अन्तर्गत जिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कार्यकर्त्ताओं को उनका अनुभव हो जाय।

कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं कि राज्य यानी सरकार का कर्तव्य तो इतना ही है कि वह कुछ सुविधाएँ तथा अन्य सामाजिक उपादान (जैसे सड़क, पानी, बिजली, यातायात आदि) प्रदान कर दे और इसके बाद का काम स्वतंत्र रूप से करने के लिए ग्रामीण जनता पर छोड़ दे। मुझे डर है कि इस प्रकार का सिद्धान्त ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल जैसी स्थिति है उसमें चल ही नहीं सकता। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल शक्ति, यातायात, संचार तथा शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाएँ ही प्रदान करनी पड़ेगी, बल्कि वहाँ ग्रामीण उद्योगों के आयोजित विकास के लिए सोद्देश्य यानी वस्तुनिष्ठ कदम भी उठाने पड़ेंगे। जिन्हें साधारण-तया 'उद्यमशील' या 'साहसिक' वर्ग कहा जाता है वे दुर्भाग्यवश न केवल ग्रामीण समस्याओं और अवस्था से परिचित ही नहीं हैं, बल्कि इस प्रकार के प्रयास में हाथ बटाने की दिशा में सोचेंगे तक नहीं।

व्यक्तिगत रूप से मैं ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में आवश्यक कौशल का विकास करने और उन्हें तकनीक ज्ञान की शिक्षा देने को बहुत बड़ा महत्व देता हूँ। मामूली जुगतवाले उपकरणों को चलाने का सहज कौशल साधारण ग्रामीणों में होता है। बहुत ही कम समय का उपयुक्त प्रशिक्षण देने पर मुझे विश्वास है कि वे छोटे-छोटे शक्ति-चालित यंत्र चला सकते हैं।

कार्यकर्त्ता

कोई वस्तुपरक कदम उठाने से पूर्व परियोजना क्षेत्रों का प्राविधिकार्थिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है। किसी परियोजना क्षेत्र के जन-शक्ति तथा सामग्री, दोनों प्रकार के साधन-स्रोतों सम्बन्धी उपयुक्त आकड़ों के बिना ग्रामीण उद्योगों का सुनियोजित कार्यक्रम सम्भव नहीं है। मेरी समझ में कार्यक्रम की सफलता बहुत-कुछ ग्रामीण उद्योगों के चुनाव के सम्बन्ध में सही निर्णय लेने पर निर्भर करेगी। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि कार्यक्रम की सफलता के लिए उन व्यक्तियों की क्षमता का भी समान महत्व है, जो काम में अपने आप को निष्ठा और विवेक के

साथ निरन्तर कठोर श्रम करते हुए लगाने के लिए उत्तरदायी ह।

रूढ़िमुक्त उपागम

अधिकांश परियोजना क्षेत्रों के सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं, किन्तु मैं सोचता हूँ कि कुछ सर्वेक्षण और अधिक परिपूर्ण होने चाहिए थे। विभिन्न राज्यों के उद्योग अधिकारियों और परियोजना अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा उनके सहयोगी प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तैयार करने में व्यस्त हैं। अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनके सम्बन्ध में किसी ने कुछ सोचा नहीं था और अनेक अनपेक्षित बाधाएँ रास्ते में आयीं। इस सम्बन्ध में मैं सबसे अधिक प्रशंसा इस बात की करता हूँ कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कार्यक्रम के प्रति रूढ़िमुक्त उपागम अपनाते हैं और इसलिए जो भी कोई समस्या उनके सामने आती है, वे उसे बड़े स्फूर्तिदायक ढंग से हल करने में अपने को लगा देते हैं। जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे कोई भ्रांति नहीं है। यह तो प्रायः अनजाने सागर की यात्रा के समान ही है। अनेक मामलों में हमें शमन करना

पड़ता है जो कि स्पष्टतः असम्यक् प्रतीत होते हैं अर्थात् बेमेल के साथ मेल बैठाना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है।

कार्यक्रम के प्रवर्तकों को न केवल उन व्यक्तियों की ओर से निष्क्रियता और विरोध मिलेगा, जो सामान्यतः नये विचारों को आत्मसात नहीं करते, बल्कि आधुनिक और नव जीवन मार्ग के अनेक विचारकों की तरफ से भी, जो ग्रामीण तथा आडम्बरविहीन यानी दीखने में भव्य, महान न लगनेवाली चीजों का उपहास करने हैं।

तथापि, मैं सोचता हूँ कि राज्यों तथा केन्द्र के स्तर पर ग्रामीण उद्योग समिति के सदस्यों और सम्बद्ध अधिकारियों में, रूढ़िमुक्त मणियों यानी तोर-तरीकों की सामर्थ्य पर दिलजमी हो जाने पर वे भी अपनाने की तत्परता एवम् जिस सुस्थिरता व आडम्बरविहीन ढंग में वे अपने आपको काम में लगाये हुए हैं, उससे मुझे यह विश्वास करने का प्रोत्साहन मिलता है कि इस कार्यक्रम को सफलता मिलनी चाहिए तथा ग्रामीण भारत की प्रगति अवरोधक समस्याओं को हल करने का सम्भवतः उससे नया मार्ग भी प्रगस्त होना चाहिए।

नयी दिल्ली • १९ अगस्त १९६३

सत्य की आराधना भक्ति है, और भक्ति 'सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा' है, अथवा वह 'हरि का मार्ग' है, जिसमें कायरता की गुजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वह तो 'मर कर जीने का मंत्र' है।

—महात्मा गांधी

गाँवों के लिए ऋण की व्यवस्था

ब्रह्मदेव मुकर्जी

ग्रामीण क्षेत्रों का विकेंद्रित आधार पर विकास करने में सम्पूर्णतः सलग्न समग्र, विकेंद्रित परतु योग्य बैंकिंग प्रवृत्ति की बड़ी आवश्यकता है। पंचायत राज की स्थापना से अब 'सामुदायिक बैंक' खोलने के विषय पर ध्यान देना होगा, जो कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए बैंकर का काम करेगा तथा ग्राम समाज के आर्थिक विकास में सहयोग देगा।

हमारे देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएँ शायद ही कहीं उपलब्ध हैं। इसका कारण यह है कि अब भी बैंकिंग कार्य अधिकतर औद्योगिक और व्यावसायिक रूप से विकसित क्षेत्रों में ही केन्द्रित है। परन्तु ग्रामीण ऋण की समस्या पर बात करना मुख्यतः कृषकों को कृषि कार्य के लिए और सामान्यतया अन्य ग्रामीण विभागों को ऋण उपलब्ध करने की बहुत ही कठिन समस्या को सामने रखना है। यदि हम इस तथ्य को समझ लें कि हमारी आबादी का करीब ८० प्रतिशत गाँवों में रहता है, उसमें से तीन-चौथाई लोग कृषि पर निर्भर हैं और वार्षिक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में करीब आधा योगदान कृषि उत्पादन का है, तो इस समस्या का महत्व स्पष्ट हो जायगा। अतः ग्रामीण ऋण की समस्या पर विचार करना एक तरह से कृषि उत्पादन के लिए संस्थागत वित्त पर विचार करना है।

कृषि के लिए निधि

यद्यपि कृषि एक कला भी है और एक जीवन मार्ग भी, फिर भी यह एक व्यापार है और अन्य व्यापारों की तरह तब तक नहीं चल सकता जब तक इसके मुख्य उपकरणों के रख-रखाव, बदल और सुधार तथा इसके उत्पादन में होनेवाले कार्यकारी खर्च के लिए निधि उपलब्ध न हो। इस तरह की निधि की आवश्यकता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि हमें कृषि में बहुत सुधार करना है। कृषि में नये और उन्नत तरीके अप-

नाने होंगे, जिनमें उन्नत कृषि सरजाम, अच्छे बीज, अधिक उर्वरक और सिंचाई जल भी शामिल हैं। गुजारेवाली कृषि के लिए भी उधार व्यवस्था आवश्यक है।

अन्य उद्योगों से भिन्न

कृषि अन्य अधिकांश उद्योगों से कई महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न है और उन्हीं भिन्नताओं के कारण कृषि के लिए उधार व्यवस्था करने में विशेष कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। बड़े उद्योगों का कार्य चन्द क्षेत्रों में केन्द्रित होता है और वे पब्लिक कम्पनी का रूप धारण कर लेते हैं, जिनका देय सीमित होता है तथा जिनके पास विस्तृत पूँजीगत साधन और बिक्री योग्य सम्पत्ति होती है, जबकि इतना बड़ा कृषि उत्पादन व्यक्तियों अथवा परिवारों के हाथ में होता है, जिनके पास अपेक्षाकृत छोटे-छोटे खेत, सीमित पूँजी और उपकरण होते हैं। इतनी अधिक संख्या में उत्पादन इकाइयाँ, हर उत्पादक के सीमित पूँजीगत साधन और धंधे का निजी स्वरूप होने के कारण ही कृषि उधार देने में कई कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। धंधे का यह निजी स्वरूप और उत्पादक के सीमित साधन ऋण देनेवाली संस्था के लिए यह और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं कि वह कर्जदार से अधिकाधिक व्यक्तिगत सम्पर्क रखे, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक है और ये किसान देश भर में फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ तक तो पहुँचना भी कठिन है, इसलिए व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखना असम्भव-सा हो जाता है।

कृषि की दूसरी विशेषता इसकी लम्बी उत्पादन अवधि है। इसकी वजह से व्यावसायिक बैंको का ऋण के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में साधारण किसानों की राह में अड़चन आती है, क्योंकि बैंक अपने पैसों का लेन-देन जल्दी-जल्दी चाहते हैं। फिर भूमि, मवेशी या उपकरण खरीदने अथवा भूमि-सुधार करने के लिए दीर्घ-कालीन ऋण का प्रश्न है। साधारण व्यावसायिक बैंकों के लिए कृषि में पैसों लगाना सामान्यतः अनाकर्षक है, क्योंकि इस काम में प्रशासन का खर्च हमेशा भारी पड़ता है और जोखिम भी अन्य व्यापारों से अधिक रहती है।

प्रशासनात्मक समस्या

किसानों को वित्त प्रदान करनेवाली किसी भी पद्धति का उसकी मारी ऋण आवश्यकताओं (लघु-कालीन, मध्य-कालीन और दीर्घ-कालीन), उत्पादन-साख और व्यक्तिगत साख को ध्यान में रखना तथा सब जोखिमों का मूल्यांकन करना होगा, ताकि यह मुनिश्चित हो सके कि किसान का कुल खर्च उसकी क्षमता से अधिक नहीं है और न ही इतना अधिक है कि उसकी उत्पादन क्षमता ही समाप्त हो जायगी एवम् वह हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा। न सिर्फ किसानों की आवश्यकताएँ ही भिन्न होगी, वरन् व्यक्तिगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना बहुत कठिन भी होगा। कृषि ऋण की मुख्य समस्या है इतनी अधिक सख्या में किसानों को आवश्यक निधि उपलब्ध करना तथा उनकी आवश्यकताओं का अलग-अलग मूल्यांकन करना, और यह समस्या आर्थिक से अधिक प्रशासनात्मक है।

इस प्रकार एक ही सम्भव रास्ता माना जाता है और वह है सहकारी समितियों के जरिये वित्त देना। कई देशों के अनुभवों ने इसे सही ठहराया है। गाँव में अथवा उसके निकट स्थित सहकारी समिति उधार लेनेवाले सभी व्यक्तियों से निकट सम्पर्क रख सकती है। सहकारी समिति के सदस्य एक-दूसरे को जानते हैं और हर कोई दूसरे के चरित्र, क्षमता और आवश्यक-

ताओं की गवाही दे सकता है तथा समिति बिना किसी विशेष खतरे के ऋण दे सकती है एवम् बिना किसी खास दिक्कत के उस ऋण में चलनेवाले कार्य का पर्यवेक्षण कर सकती है। अपने कार्य में स्वायत्त होने के फलस्वरूप सहकारी समिति अपनी नीतियाँ और व्यवहारों में परिवर्तन कर सकती है, ताकि वे क्षेत्र अथवा उधार लेनेवालों की अवस्था के अनुरूप हो सके। इन सबसे भी अधिक सहकारी दृष्टिकोण सदस्यों में स्वयं-सेवा, मितव्ययिता और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने की कोशिश करता है और समुदाय में सामाजिक स्निग्धता का विकास करता है। यह इस तथ्य का यथार्थ रूप में सामना करता है कि बहुत हद तक ग्रामीणों को अपनी आय तथा अपने ही साधनों पर निर्भर करना पड़ेगा, और यह विश्वास रखता है कि व्यक्तिगत तौर से कहीं अधिक वे सहकारी तौर पर बढ़ सकते हैं।

सहकारिता का प्रारम्भ

भारत में सहकारिता का आरम्भ इस शताब्दी के आरम्भ में हुआ। परन्तु अंग्रेजी शासनकाल में इसने बहुत ही कम प्रगति की। हमारी पंच वर्षीय योजनाओं में सहकार को दोनों ही दृष्टियों से—इसके व्यवहारिक महत्व और समाजवादी समाज तथा लोकतांत्रिक कल्याण राज्य सम्बन्धी देश की बुनियादी नीति के अनुरूप होने की दृष्टियों—बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में यह कहा गया—“लोकतांत्रिक आधार पर आर्थिक विकास अनन्त रूपों में सहकार को प्रयुक्त करने का बृहत् क्षेत्र प्रस्तुत करता है। समाजवादी समाज की हमारी पद्धति में बहु-संख्यक विकेन्द्रित इकाइयों का निर्माण—कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में—शामिल हैं। सहकारी सगठन का जो लाभ है, उसका मुकाबला न निजी उद्योग कर सकता है और न राज्य स्वामित्व। विशेष रूप से यह समान रूप से सामाजिक और वैयक्तिक प्रेरणाओं का लाभ उठा कर समाज के लिए बहुमूल्य परिणाम प्राप्त करने के साधन प्रस्तुत करता है।”

अब तक जो प्रगति हुई है, वह महत्वपूर्ण है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या १९५०-५१ के १,०५,००० से बढ़ कर १९६१-६२ में २,१५,००० हो गयी। उनकी सदस्य संख्या ४० लाख ८ हजार से बढ़ कर १ करोड़ ९५ लाख ६ हजार हो गयी है और संचालन पूजी ३७ करोड़ २५ लाख रुपये से बढ़ कर ३ अरब २५ करोड़ २५ लाख रुपये। ये आंकड़े समूचे देश की दृष्टि से आकर्षक हैं, देश भर में प्रगति समान नहीं हुई है और समस्या का सिर्फ एक छोर ही छूआ जा सकता है। जबकि देश के कुछ भागों में हुई प्रगति उत्साहजनक रही है, कई अन्य भागों में वह बड़ी निराशाजनक रही है। सहकारी विभाग के विकासार्थ बहुत विचार, आयोजन और प्रयास किये गये हैं, परन्तु विश्वास के साथ यह कहा जा सके कि हम उस प्रशस्त पथ तक पहुँच गये हैं जोकि हमें निर्दिष्ट लक्ष्य तक ले जायगा, मुझे इसमें सन्देह है। मैं अपने सहकारी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार में चर्चा नहीं करूँगा जो कि अभी तक कमजोर बने हुए हैं, और न उन दोषों के विषय में ही जो कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मौजूद है और न उन कारणों पर ही, जो कि प्रगति की राह में बाधक बने हैं। इन पर कई समितियों, कार्यकारी दलों, आदि द्वारा विचार किया जा चुका है तथा बड़ी-बड़ी रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिससे सबको इसकी जानकारी मिल सके। अतः मैं प्रश्न के अन्य पहलुओं का जिक्र करूँगा।

ग्रामीणों को ज्ञान देना

यह महसूस करना आवश्यक है कि यह बड़ा ही कठिन काम है। इसमें लाखों ग्रामीणों को नये विश्वासों और विचारों में शिक्षित, संगठित और लक्ष्यमुखी बनाना शामिल है ताकि वे बुद्धिमानीपूर्वक और सक्रिय ढंग से लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में काम कर सकें और अपने को आर्थिक और सामाजिक कल्याण के नये कार्यों में लगा सकें। इतने बड़े देश में और वह भी अशिक्षित और परम्परामुखी लोगों में ऐसा परिवर्तन लाना

जटिल, कठिन और समय लगनेवाला कार्य होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सहकारी कार्यशीलताएँ ग्रामीणों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण से बहुत ही निकट रूप में सम्बन्धित हैं, जो कि प्रत्यक्ष दृष्टि-गोचर हो तथा उसमें जनता का दृढ़ विश्वास पैदा हो।

यदि कृषि को सुधारने तथा ग्रामीण औद्योगीकरण के विकास में पर्याप्त सफलता नहीं मिली तो सहकार आन्दोलन के सफल होने की आशा बहुत कम रहेगी, यद्यपि ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में सफलता किसी हद तक सहकार के विकास में प्राप्त सफलता पर निर्भर करेगी। ठोस और अच्छा आयोजन तथा आयोजन का योग्य कार्यान्वयन आवश्यक होगा। अकेली कृषि से ग्रामीण क्षेत्र के सम्पूर्ण श्रमिकों को रोजगारी नहीं मिल सकती, जब तक कि वह रोजगारी गुजारे अथवा गुजारे से भी निचले स्तर की न हो। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण औद्योगीकरण रोजगारी के अन्य पथ प्रशस्त नहीं करता तो अधिकांश श्रमिक औद्योगिक केन्द्रों की ओर भागते ही रहेंगे और इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ पैदा करते रहेंगे।

आर्थिक रूप से प्राणवान उद्योग

परन्तु अतिरिक्त श्रम-शक्ति को रोजगारी अथवा पूर्ण रोजगारी प्रदान करने और ग्रामीणों के लिए केवल कृषि अर्थ-व्यवस्था के स्तर से, भले ही वह कितनी भी सुधरी क्यों न हो, ऊँचे स्तर का जीवन प्राप्त करने हेतु धन-उत्पादन में वृद्धि करने, इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण औद्योगीकरण का कार्यक्रम सुनियोजित हो तथा वह कृषि विकास के साथ-साथ बड़े पैमाने के औद्योगिक विकास के साथ समन्वित हो।

मैं ग्रामीण औद्योगीकरण के विषय में कह रहा हूँ, न कि ग्रामीण उद्योगों अथवा ग्रामोद्योगों के बारे में। कुछ और उत्तम साधन प्राप्त न हो जाने तक ग्रामोद्योगों का पुनर्स्थापन और विकास कार्य जारी रखना होगा, उन्हें हमेशा निचली तकनालाँजी तक ही नहीं रखा जा

सकता। परम्परागत ग्रामोद्योगों के स्थान तथा उन्हें यथावत् सरक्षित रखने की आवश्यकता पर हाल के वर्षों में काफी भावात्मक, निराधार और प्रायः परि-भ्रमित विचार व्यक्त किये गये हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम की सफलता वैसे उद्योगों के चुनाव पर ही निर्भर करेगी जो कि आर्थिक रूप से जीवित रहने योग्य, प्राणवान हो अथवा जिन्हें सीधे ही वैसा बनाया जा सके और जो कि निरन्तर उन्नत तकनालॉजी अपनाने योग्य हो।

सही दृष्टिकोण से विचार करने पर ग्रामीण औद्योगीकरण का उद्देश्य प्रो गाडगिल के शब्दों में यह होना चाहिए—“देश का औद्योगीकरण अधिकाधिक विकेन्द्रित, छोटे से छोटे पैमाने पर और अधिक से अधिक रोजगारी क्षमता के साथ होना चाहिए जो कि योग्य तकनीक और विकास प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।” इस सन्दर्भ में कृषि विकास की चर्चा करते वक्त मैं अन्ततः कृषि को योग्य व्यावसायिक कार्य के रूप में विकसित करने के विषय में सोच रहा हूँ। विकेन्द्रित क्षेत्रीय आधार पर आयोजन के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास और औद्योगिक विकास के बीच अधिकाधिक आपसी सहायता और परस्पर निर्भरता लाना सम्भव होना चाहिए। कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होनेवाले लघु उद्योगों और देश के औद्योगिक केन्द्रों में जमे बड़े उद्योगों के बीच भी आपसी सहायता और परस्पर निर्भरता लाने के लिए आयोजन करना सम्भव है।

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को साख योग्य बनाना

ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए ऋण की व्यवस्था करने में भी वैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसा कि कृषि के विकास में, और कारण भी बहुत-कुछ वही रहेंगे। दोनों ही मामलों में सामान्य बैंकिंग माप से साख की दर निम्न रहेगी। परन्तु दोनों ही मामलों में आवश्यक ऋण की व्यवस्था करनी होगी ताकि उनकी साख बढ़ सके। इससे परिस्थिति की जटिलता सामने

आती है, पर साथ ही इस बात का विशाल व्यापक महत्व भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए एक ठोस योजना अपनाना कितना आवश्यक है जो कि उस अर्थ-व्यवस्था की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए—जैसे बढ़ती आबादी, समग्र रूप से स्रोतों की अपर्याप्तता, गांवों में तकनीकल ज्ञान तथा प्रबन्धकीय योग्यता की कमी, प्रारम्भ में सीमित बाजारों का होना आदि—उसे चिरविकासशील निवेश-स्तर के लिए एक प्राणवान और साख के लायक अर्थ-व्यवस्था बना दे। ग्रामीण ऋण तो सिक्के का एक ही पहलू है, दूसरा पहलू है ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को साख के लायक बनाना। इन दोनों समस्याओं को सिर्फ इकट्ठे ही हल किया जा सकता है।

विकेन्द्रीकरण

यह प्रश्न किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों का जैसा विकास मैं चाहता हूँ, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? मेरा उत्तर है कि इसकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि लोकतांत्रिक राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में विकेन्द्रित सामाजार्थिक समुदायों के विकासार्थ एक सामान्य नीति नहीं अपनायी जाती। केन्द्रित उपागम तो असफल ही रहेगा। मैं यहाँ इस प्रश्न पर चर्चा नहीं करूँगा कि क्षेत्रीय विकास के लिए विकेन्द्रित आयोजन किस प्रकार आम तौर पर तथा समग्र राष्ट्रीय आयोजन से पूर्णरूपेण सगत है। मेरी समझ से इस पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पचायत राज जैसे दूरगामी और क्रांतिकारी विचार अपना कर तथा हमारे विकास कार्यक्रम में सहकारी सगठन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर विकेन्द्रीकरण की नीति स्वीकार कर ली है।

विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए सही किस्म के स्थानीय नेतृत्व का विकास बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और दूरगामी विकेन्द्रित दृष्टिकोण ही ऐसे नेतृत्व का विकास कर सकेगा। पचायत राज योजना तभी सफल होगी जबकि उसमें निहित विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो। घोर गरीबी में जीवन बिता रहे ग्रामीणों को सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पचायत राज सस्थाएँ उनकी हैं और उन्हें बहुत-से काम दिये जा रहे हैं, बल्कि उन्हें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि ये अधिकारी उनकी आर्थिक समस्याओं को योग्यतापूर्वक सम्भाल रहे हैं। इस कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त आर्थिक-स्रोत प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। उन्हें गाँवों में कृषि-सुधार और उद्योगों के विकास का कार्य देखना होगा जो कि बेकारों तथा अर्धबेकारों को रोजगारी देगा, न कि सिर्फ वे असैनिक कार्य देखने होंगे जो कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ग्रामीणों की आर्थिक अवस्था सुधारने हेतु मैं जिला परिषदों और पचायत समितियों द्वारा भी सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्योग आरम्भ किये जाने की कल्पना करता हूँ, जिस तरह कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी कुछ सार्वजनिक सस्थान चलाती हैं।

सहकारी आधार

बेशक इन उद्योगों को वैसा होना होगा, जो कि अधिकतर स्थानीय प्रयासों से विकसित किये जा सकें और जिनका प्रबन्ध स्थानीय अधिकारीगण कर सकें। इसे फलित होने में कुछ समय लग सकता है, पर लक्ष्य यही होना चाहिए। इनके अतिरिक्त सहकारी आधार पर गठित अन्य बहुत-से उद्योग होंगे। हमारे आयोजन का सामाजिक उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, भले ही कृषिक रूप में हो अथवा औद्योगिक, यथा सम्भव सहकारी आधार पर होना चाहिए। यदि ग्रामीणों को अपने उद्योग स्वयं ही विकसित करने हैं, जोकि अधिकतर अपने ही प्रयासों और स्थानीय स्रोतों पर आधारित होना चाहिए, तो अधिकतर इनका विकास सहकारी आधार पर करने के सिवा और कोई चारा नहीं दिखाई देता। पर यह समझ लेना गलत होगा कि सहकारी आधार पर सगठन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था, जिनकी तकनालाजी उन्नत नहीं है, तथा

ग्राम स्वावलम्बन के आधार पर बिक्री के लिए ही आवश्यक है। सहकारी आधार पर योग्य उत्पादन, ठोस व्यापारिक प्रबन्ध और निरन्तर उन्नत हो रही तकनालाजी का सगठन करना सम्भव है और इसका कई उन्नत देशों में प्रदर्शन भी किया गया है।

स्रोतों का स्थानीय विकास

अब मैं इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूँ कि मेरी कल्पना के ग्रामीण विकास हेतु किस प्रकार पर्याप्त स्थानीय स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। स्थानाभाव के कारण इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। सामान्य उद्देश्य, जिसे कि मैं कुछ महत्वपूर्ण समझता हूँ और जो कि मेरी राय में पर्याप्त वैधता भी रखता है, यह है कि मेरे बताये अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के विकासार्थ आवश्यक स्रोत का बहुत अधिक भाग गाँवों में ही पैदा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की दीर्घ-कालीन वैधता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ समय के लिए बाहरी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह की बाहरी सहायताएँ पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती हैं, खास कर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकार, कृषि, ग्रामोद्योग आदि कार्यक्रमों के लिए। मैं यह कल्पना करता हूँ कि पूर्ण विकसित हो जाने पर पचायत राज सस्थाओं को कर के रूप में भी खासी रकम उगाहनी चाहिए। सब कर उनके द्वारा लगाये जाने अथवा उगाहने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ भूमि-राजस्व जैसे कर राज्य-कर रह सकते हैं, परन्तु पचायत राज सस्थाओं को उसमें से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। अन्य कर भी वितरित होनेवाले करो की श्रेणी में आ सकते हैं। परन्तु पचायत राज सस्थाओं द्वारा लगाये और उगाहे जानेवाले करो की सूची बढ़ती जायेगी और उससे अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर उन्हें राज्य सरकार से ऋण मिलना चाहिए। उन्हें इस योग्य होना चाहिए कि वे बाजार से स्वयं भी ऋण प्राप्त कर सकें। सहकार आन्दोलन और इसकी बैंकिंग

पद्धति के मजबूत होने के साथ साथ सहकारी विभाग द्वारा अधिकाधिक निधि प्राप्त की जायगी और विकास कार्यों के लिए प्राप्त होगी—सहकारी समूहों की अंश पूँजी बढ़ा कर, सरक्षित निधि बना कर, बाहरी साधनों से उधार लेकर।

संयुक्त बैंकिंग स्वरूप

पंचायत राज सस्थाओं को मेरी कल्पना के अनुरूप विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने हेतु, जो कि उन्हें अन्ततः अपना ही चाहिए, बैंकिंग सेवा की आवश्यकता होगी जिसे कि सहकारी माध्यम के जरिये उपलब्ध किया जा सकेगा। अब तक हमारा सहकार आन्दोलन प्रधानतः कृषि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही विकसित हुआ है। काफी हद तक ग्रामीण औद्योगीकरण हो जाने के बाद भी, ग्रामीणों का मुख्य धंधा कृषि ही रहेगा। अतः मुझे शक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में सहकारी बैंकिंग माध्यम कोई विशेष योगदान दे सकेगा। उसका झुकाव कृषि की ओर ही रहनेवाला है। बाद में पंचायत राज सस्थाओं को कई किस्म की बैंकिंग सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, जैसे बढ़ते नकद लेन-देन का प्रबंध करने, पूँजीगत और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद देने, उनके उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद देने, उनके उद्योगों के लिए संचालन आदि के लिए।

हमें यह भी ध्यान में रखना ही चाहिए कि जैसे-जैसे हमारी कृषि व्यापारिक बनती जाती है, जैसा कि होना ही चाहिए—इसमें लोगों को उच्च जीवन स्तर उपलब्ध करने तथा बढ़ते पैमाने के विकास कार्यक्रम को बनाये रखने के लिए भी—इसे काफी बड़े पूँजी-निवेश की जरूरत पड़ेगी। मेरी राय में हमारे देश में कृषि के लिए आर्थिक सहायता हेतु सहकारी और व्यावसायिक बैंकों का मिश्रित दृष्टिकोण रखनेवाला बैंक कृषकों के लिए अधिक उपयोगी होगा। कृषि और ग्रामीण-औद्योगीकरण, दोनों ही के विकास पर आधारित ग्राम

विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्ततः संयुक्त बैंकिंग प्रणाली ही लाभदायक होगी।

एक सामुदायिक बैंक की भी आवश्यकता होगी, जोकि पंचायत राज सस्थाओं के लिए बैंक का काम करने और स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हो। यह सुझाव देते वक्त इतना तो मैं मान ही लेता हूँ कि पंचायत राज सस्थाएँ मेरी कल्पना के अनुरूप विकेन्द्रित स्थानीय अधिकारियों के रूप में विकसित हो जायेंगी। यह आशा करना बेकार है कि बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों की शाखाएँ यह कार्य कर सकती हैं। यह भी कल्पना करना कठिन है कि कोई सहकारी समिति अथवा बैंक इतना बड़ा काम कर सकता है। जिस सामुदायिक बैंक का मैं सुझाव दे रहा हूँ, वह सहकारी और व्यावसायिक बैंकों दोनों के अच्छे और मजबूत पहलुओं का मिश्रण होना चाहिए। उन्हें बहुत ही विकेन्द्रित आधार पर और स्थानीय अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखते हुए कार्य करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राज्य वित्त निगमों, सहकारी बैंकों तथा अन्य व्यावसायिक बैंकों जैसी कई वित्तीय सस्थाओं की भागीदारी में इन्हें स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि चन्द विकास वित्तीय सस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। इस तरह के छोटे बैंकों के योग्य ढंग से कार्य न करने का कोई कारण ही नहीं है, यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक जैसी अनुभवी सस्थाओं द्वारा उनके नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए कोई अच्छी पद्धति निकाली जाय।

अमेरिका में छोटे बैंक

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि 'सामुदायिक बैंक' पर मैंने इतना अध्ययन नहीं किया है कि उसे विस्तृत रूप से बता सकूँ, परन्तु मैं यह महसूस करता हूँ कि यह विचार आजमाने लायक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बैंकिंग इतिहास में—देश के विकास के प्रारंभिक काल में जबकि आबादी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी और नये-

नये क्षेत्र बन रहे थे—छोटे-छोटे बैंको ने सामुदायिक बैंक के रूप में बहुत ही मूल्यावान् कार्य किया। नये-नये समुदायों के साथ उनका भी विकास और उत्थान हुआ और उन्होंने उन समुदायों के विकास में सहयोग दिया। वे जिस समुदाय के बीच कार्य करते थे, उसके प्रति बड़े ही ईमानदार थे। इस अमेरिकी बैंकिंग पद्धति के अच्छे-बुरे अनुभवों से हम लाभ उठा सकते हैं। मैं मुख्य रूप से यही कहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास विकेन्द्रित आधार पर और कृषि-औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के विकास के जरिये करने पर हमें समर्थ, विकेन्द्रित, परन्तु योग्य बैंकिंग सेवा की—जोकि पूर्णतः इस विकास कार्य के लिए ही हो—जरूरत पड़ेगी। इसकी नीतियों, कार्य और कार्य-विधियाँ क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा जिसकी सेवा करनी है उसकी अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए।

इस विचार का एक अनुसिद्धान्त यह है कि इस बैंकिंग स्वरूप को उस समुदाय की बचत और व्यापार का

आश्वासन दिया जाना चाहिए, जिसकी इसे सेवा करनी है। जैसा कि मैंने कहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतर अपने ही साधनों के आधार पर विकसित होना है। लोगों की बचत के लिए आज व्यावसायिक बैंको, सहकारी बैंको, सरकारी अल्प बचत अभियानों के बीच प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। व्यावसायिक बैंक गाँवों में अपनी शाखाएँ खोल रहे हैं। यदि बड़े रूप में अन्ततः विकेन्द्रित विचारधारा को सफल होना है तो इन माध्यमों के बीच कार्य-क्षेत्र का किसी किस्म का बटवारा होना ही चाहिए। गाँवों में कार्य कर रही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच काफी सहयोग पैदा करना कठिन नहीं होना चाहिए, जोकि सब के लिए लाभदायक होगा। रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंको, विकास बैंको और सहकारी बैंको के बीच इस तरह के सहयोग और समझ-बूझ की आवश्यकता हमारे आर्थिक विकास के अन्तर्गत स्पष्ट होती जा रही है।

बम्बई ६ सितम्बर १९६१

विचार ही मनुष्य को नागरिक बनाता है। इसलिए उसे अपने श्रम की अवधि का ऐसा विभाजन करना चाहिए कि रचनात्मक कार्यों के लिए समय बच सके। यह स्पष्ट है कि मनुष्य जो शक्ति खर्च कर सकता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी सीमा होती है, परन्तु अपने लिए सरकार उसे शक्ति खर्च करने की जो अनुमति दे सकती है उसकी भी नागरिक, सामाजिक दृष्टि से सीमा होगी। जो लोग यत्र के संचालन में उसकी देखरेख में अपनी शक्ति खर्च करते हैं वे, जैसा कि अरस्तू ने अनुभव किया, जीवन के उच्चतम कार्यों के लिए अयोग्य हो जाते हैं, बशर्ते कि उनके पास यत्र चलाने में उसकी देखरेख के अलावा दूसरे काम के लिए काफी अवकाश हो। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में कई घण्टों तक काम करने के कारण व्यक्तित्व में अवह-द्धता का पैदा होना एक आम बात थी और उसके परिणामों की जो जाँच की गयी उससे यह स्पष्ट हो गया है। पुरुष और स्त्रियों दिन भर मेहनत करने के बाद जब घर लौटते थे तो थकान के कारण उनकी सोचने-विचारने की शक्ति लुप्त हो जाती थी, यहाँ तक कि उनकी भावनाएँ भी मन्द पड़ जाती थी। उनके यत्र ही उनके मालिक थे। उनके पास अवकाश नहीं होता था, जिसमें वे अपने आप को पहचान सके। वे तो केवल लगातार मेहनत के जीवन से ही परिचित थे। समुचित घण्टों तक श्रम करने का अधिकार ही मनुष्य को अपने मस्तिष्क का क्षेत्र पहचानने का अधिकार प्रदान करता है। यह मानव जाति की बौद्धिक विरासत का मूलमंत्र है।

—हैरोल्ड जे लास्की : ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स

हमारी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर खादी का प्रभाव

अरुण चन्द्र गुहा

हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका निर्णय इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि समाज के सबसे गरीब वर्गों को राहत प्रदान करने, उनकी मदद करने में वह किस हद तक सफल हुआ है।

भारत सरकार को खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम राष्ट्र पिता की प्रत्यक्ष देन के रूप में मिला है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की समस्त अवधि में इस कार्यक्रम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उस वक्त प्रत्येक कार्यकर्त्ता खादी व ग्रामोद्योगों का सकल्प लिये हुए था। अतएव समग्र सरकार अथवा सरकार में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों का भार वहन करनेवाले व्यक्तियों का इस कार्यक्रम से भावात्मक सम्बन्ध है तथा वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि भावात्मक सम्बन्ध के कारण ही हमारी सरकार ने इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने का उत्तरदायित्व लिया है। भारत एक गरीब देश है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत की प्रति व्यक्ति आय १०० रुपये वार्षिक से कुछ अधिक थी। आज भी लाखों व्यक्ति या तो बेरोजगार हैं अथवा उन्हें बहुत ही कम रोजगार उपलब्ध है। किसी भी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे लाखों बेरोजगार अथवा अल्प-रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों के लिए काम का प्रबन्ध करके उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाये। काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से शहरी बेरोजगारी के कुछ चित्र हमारे सामने हैं, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की रोजगारी की स्थिति का कोई खाका हमारे सामने नहीं है, वह अनुमान का विषय ही बना हुआ है। तिस पर भी यह मालूम है कि अविकाश ग्रामीणों के पास वर्ष में १५० दिन का ही काम रहता है और इस प्रकार उन्हें आंशिक रूप से ही काम प्राप्त है।

खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम बनाने का यही आर्थिक

और सामाजिक कारण है। जबसे हम आजाद हुए हैं, ग्रामीण बेरोजगारों तथा अल्प-रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों को रोजगारी का वैकल्पिक साधन प्रदान करने के विचार से हम यह कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। लगभग १६ वर्ष तक कार्यक्रम चलाने के पश्चात् इस बात का मूल्यांकन करना समीचीन ही होगा कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। बड़ी दृढ़तापूर्वक ऐसा कहा जाता है कि गत १५-१६ वर्ष में समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्तियों की वास्तविक आय बड़ी नहीं है, हो सकती है कि रुपये-पैसे की शब्दावली में उनकी आमदनी बड़ी हो, लेकिन जिन सेवाओं तथा सामग्रियों का वे उपभोग करते हैं उनकी दृष्टि से नहीं। अतएव अब इस चीज का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि इस कार्यक्रम ने हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप में क्या कोई परिवर्तन लाया है।

खादी उद्योग

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के नवीनतम वार्षिक विवरण (१९६१-६२) से पता चलता है कि करीब १७ लाख व्यक्ति खादी कार्य में लगे हैं तथा उनमें से अधिकांश आंशिक समय का काम करनेवाले हैं। इन १७ लाख व्यक्तियों में कमीशन ने १७ करोड़ से कुछ अधिक रुपये वितरित किये, इसलिए इन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय लगभग १०० रुपये वार्षिक अथवा ८३३ रुपये प्रति माह हो सकती। जिस देश में नितल श्रेणी के लोगों की आय करीब आठ-दस रुपये मासिक ही हो,

वहाँ और आठ रुपये की आमदनी कोई नगण्य नहीं है। तृतीय योजना के प्रतिवेदन में लगाये गये हिसाब के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या १ करोड़ ७५ लाख (द्वितीय योजना के अन्त में बचे करीब ६० लाख व्यक्तियों और रोजगारी चाहनेवाले नये १ करोड़ १५ लाख से कुछ अधिक व्यक्तियों सहित) होगी। यदि खादी कार्यक्रम ने १७ लाख व्यक्तियों को आशिक काम और औसतन रूप से लगभग १०० रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी प्रदान की है तो उसने तकरीबन १० प्रति शत ग्रामीण बेरोजगारों की मदद की है। यह कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, इस हिसाब में जो असह्य व्यक्ति अल्प-रोजगार प्राप्त हैं, उन्हें वस्तुतः शामिल नहीं किया गया है।

राज्य मण्डल

समग्र खादी-कार्यक्रम के अन्तर्गत १७ करोड़ से कुछ अधिक रुपये की खादी बिक्री और उसी वर्ष में कमीशन ने अनुदान तथा ऋण के रूप में लगभग १८ करोड़ रुपये वितरित किये। प्रतिवेदन का अध्ययन करने पर पाठक को आश्चर्य होता है कि कमीशन ने १९६१-६२ में १७ करोड़ ९३ लाख रुपये वितरित किये और समग्र कार्यक्रम ने खादी का उत्पादन भी १७ करोड़ ५४ लाख रुपये का ही किया। कोई यह मानने के लिए उद्यत हो सकता है कि यह समग्र रकम खादी-कार्यक्रम में लगे सूतकारों और बुनकरों को राज्य की तरफ से एक प्रकार से सदावर्त के रूप में दी गयी। किन्तु मेरी दृष्टि से यह सही मूल्यांकन नहीं है, प्रति वर्ष जो वितरण होता है वह सब का सब सरकार से नहीं मिलता। इसका कुछ हिस्सा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की कमाई होता है, जिसे खादी का बिक्री मूल्य मिलता है, और उसका कुछ हिस्सा पहले ऋण के रूप में दी गयी रकम की पुनः अदायगी के रूप में वापस मिलता है। इस सम्बन्ध में एक चिन्ताजनक बात यह है कि बकाया ऋण की रकम बढ़ती जाती है—फिलहाल ३५ करोड़ ५८ लाख रुपये बकाया है। यह प्रश्न उठ सकता है कि यह समूची रकम

कभी वापिस आयेगी भी या नहीं।

दो वर्ष पूर्व ससद द्वारा नियुक्त अनुमान समिति ने खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के काम का मूल्यांकन किया था। उसने बताया था कि कमीशन ने राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों को २२ करोड़ से ज्यादा रुपये दिये, लेकिन उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल १ करोड़ ४७ लाख रुपये के लिए ही प्राप्त हुए। अतएव हिसाब-किताब और लेखा-परीक्षण की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि २१ करोड़ रुपये का अब भी कोई हिसाब नहीं है। हम आशा कर सकते हैं कि राज्य मण्डल अब हिसाब-किताब और लेखा-परीक्षण सम्बन्धी कार्यों के मामले में ठीक से काम कर रहे होंगे। हमारा एक दुःखपूर्ण अनुभव यह है कि जहाँ कमीशन निष्ठापूर्वक और तहेदिल से कार्य करना चाहता है, वहाँ राज्य मण्डल वैसा ही दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते। राज्य मण्डलों के गठन और कार्य में प्रायः राजनीति की प्रधानता रहती है। हो सकता है कि कार्यक्रम के संचालन का काम राज्य मण्डलों को देने और स्वयम् कमीशन के पास मात्र रुपये-पैसे वितरित करने तथा प्रभावविहीन निरीक्षण या व्यवस्था का अधिकार रखने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं रहा हो।

हमें डर है कि कमीशन कभी-कभी बहुत ही विस्फुरित कार्यक्रम हाथ में लेता है। कताई, बुनाई और खादी की बिक्री कमीशन के खादी विभाग का मुख्य कार्यक्रम है, अब उसने उत्पादन और बिक्री का काम राज्य मण्डलों के पास छोड़ने का तय किया है। लेकिन हम विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि कपास उत्पादन में प्रयोग व अन्वेषण के क्षेत्र में कदम रखना इसके लिए बुद्धिमानी का काम था। यह काम उपयुक्त अधिकारियों-केन्द्रीय कपास समिति और कृषि मन्त्रालय-के लिए छोड़ना चाहिए था। इस काम के अनुपात के आधार पर इस बात के कारण है कि कमीशन को विस्तृत पैमाने पर कृषि-विषयक परीक्षण और अन्वेषण करना पड़ेगा। इन सबके लिए विशिष्ट माध्यम, संस्थाएँ हैं।

कुटीरद्योगो में शक्ति के उपयोग का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन रहा है। जहाँ तक हम इस सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों को समझ पाये हैं, उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक का श्रम कम करने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की यात्रिक शक्ति का समर्थन किया है। जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उन्होंने बहुत जोर दिया वह यह था कि उत्पादन के साधन और उससे प्राप्त फल पर मिल्कियत कामगार की होनी चाहिए और यह कि उसे इन साधनों का गुलाम नहीं बना देना चाहिए। हाथ से सिलाई करने के स्थान पर, महिलाओं को सिलाई करने के थका देनेवाले श्रम से बचाने के लिए, सिलाई मशीन के उपयोग को तरजीह देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। फिर भी, ग्रामोद्योगों में शक्ति का उपयोग स्वीकार करने में कमीशन को काफी हिचक है। कुटीर उद्योगों में शक्ति के इस्तेमाल के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति ने शक्ति के उपयोग की सिफारिश की, किन्तु प्रतिवेदन से पता चलता है कि कमीशन अब भी हिचकिचा रहा है और “विकेन्द्रित आधार पर शक्ति उत्पादन अथवा जनन के लिए कदम उठाने की” कोशिश कर रहा है।

शक्ति-जनन

कमीशन का विचार है कि “स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से विकेन्द्रित आधार पर शक्ति उत्पादन को एक प्राथमिक उद्योग समझना चाहिए।” हमें डर है कि कमीशन एक कठिन मार्ग अपना रहा है, उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। शक्ति उत्पादन के लिए प्रायः एकाधिकृत तंत्र सरकार—उसका सिचाई मंत्रालय तथा उसके सहायक अभिकर्ता—है। यह एक विशिष्ट विषय है और सस्ती कीमत पर शक्ति पैदा करने का प्रत्येक उपाय किया जाना चाहिए। इकाई जितनी ही बड़ी होगी, शक्ति जनन की लागत उतनी ही कम होने की अपेक्षा है।

कुटीरद्योगों में एक कमी यह है कि उनका उत्पादन

खर्च कारखानों के उत्पादन खर्च से अधिक होता है। लागत कम करने का एक साधन शक्ति का इस्तेमाल है। अब यदि कमीशन के विकेन्द्रित शक्ति उत्पादन के विचार को अमल में लाया जाता है तो इसका मतलब है कि कुटीर उद्योगों को बिजली के लिए अधिक खर्च वहन करना पड़ेगा। और फिर, ग्रामीण उद्योग शक्ति के विकेन्द्रित उत्पादन के लिए प्रतीक्षा करते हैं तो हमें डर है कि उन्हें काफी लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ेगा। कमीशन गोबर गैस और सौर ऊर्जा के उपयोग पर विचार करता आ रहा है। इस सम्बन्ध में काफी समय तक प्रचार करने के बाद अब भी यह देखना है कि ग्रामीणों को उक्त योजनाएँ कब वास्तविक सेवाएँ प्रदान करेगी। प्रात्यक्षिक के तौर पर उत्पादन और व्यावसायिक उत्पादन के मध्य विभेद करना होगा।

निराधार भय

राष्ट्र या राष्ट्र के अपेक्षाकृत गरीब लोगों तक की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करनेवाले मामलों में बहुत अधिक भावना-प्रधान या सैद्धान्तिक होने से कोई लाभ नहीं है। कमीशन को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि बड़ी इकाइयों की शक्ति का कुटीरद्योगों में इस्तेमाल करने से वे दूषित हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में सर्व प्रधान विचार यह होना चाहिए कि शारीरिक श्रम तथा उत्पादन लागत कम हो और फलस्वरूप ग्रामीण कारीगर को कुछ आराम मिले एवम् अधिक प्राप्ति हो। मानवीय श्रम को उचित प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और उसे पशुवत श्रम नहीं समझना चाहिए।

हम ने खादी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह प्रायः अन्य सभी ग्रामोद्योगों पर समान रूप से लागू हो सकता है। हम सोचते हैं कि खादी की अपेक्षा हाथ कागज में शक्ति का उपयोग अधिक आवश्यक है, साबुन उत्पादन में भी शक्ति के इस्तेमाल से अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। यह शका पैदा हो सकती है कि शक्ति के प्रयोग से कार्यक्रम की रोजगारी देने सम्बन्धी क्षमता कम हो जायेगी। किन्तु वस्त्र तथा अन्य उपभोक्ता सामग्री

की अपेक्षाकृत कम पूर्ति होने की वजह से इस प्रकार का डर न्यायोचित नहीं है। इसके सिवाय बिजली के प्रति जो आपत्ति है उसी आधार पर 'गियर' और 'बाल बियरिंग' सहित चार या छ तकुओ के अम्बर चरखों से भी बचना चाहिए था।

अम्बर चरखा

चरखे में सुधार करने के लिए कमीशन ने अनेक प्रयोग किये हैं। अम्बर चरखा कार्यक्रम के भविष्य का मूल्यांकन करना लाभप्रद होगा। करीब चार लाख अम्बर चरखे वितरित हुए हैं। उनमें से दो लाख के करीब चरखे निष्क्रिय पड़े हैं। कमीशन अब उन्हें छ तकुओवाले चरखों में बदलने और चलाने में हल्के तथा आसान बनाने के लिए उनकी बनावट में कुछ सुधार करने की भी सोच रहा है। ऐसा करने से उत्पादन तथा आमदनी बढ़ सकेगी। इन पुराने चरखों को फिर से दूसरे नमूने में बदलने का कार्यक्रम चलाने से पूर्व यह देखना बेहतर होगा कि अन्ततोगत्वा कहीं अच्छी किस्म के नये चरखों का उत्पादन करना तो सस्ता नहीं पड़ेगा। रचनात्मक काम करनेवाले प्रमाणित सगठनों से पुराने अम्बर चरखे वापिस लेने के लिए कहा गया है, लेकिन वे सभी ऐसा करने में हिचकिचा रहे हैं।

अम्बर चरखे को उच्च उत्पादकता और अधिक लाभदायक आय करवानेवाले बेहतरीन चरखे के रूप में बड़ी आशावादिता के साथ प्रारम्भ किया गया था। 'गियर' और 'बाल बियरिंग' से युक्त तथा चलाने में आसान हो, ऐसे चरखे के लिए आज भी व्यापक क्षेत्र व गुंजाइश है। यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार के चरखे में शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने पर हमें कुटीर उद्योग स्तर पर चलाने के लिए एक प्रकार का कताई यंत्र मिल जायेगा। बुनाई में शक्ति का प्रयोग करने के प्रति अब भी प्रतिरोध है। हम मानते हैं कि हाथ करघे के स्थान पर शक्ति करघे का अर्थ है कार्यक्रम की रोजगारी देने की क्षमता में कमी, किन्तु हम सोचते हैं कि कपड़े की कोई बहुत अधिक पूर्ति

न होने के कारण इस प्रकार का डर परिपूर्णत न्यायसंगत नहीं है।

यह सच है कि रोजगारी के पहलू का महत्व है, लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी समान महत्व है कि काम में लगे व्यक्ति को उस काम से लाभदायक आय का प्राप्त होना सुनिश्चित हो। कमीशन इस सवाल पर विचार कर सकता है कि शक्ति चालित करघों के साथ शक्ति से चलाये जानेवाले कताई यंत्र को कुटीर उद्योग का आधार माना जा सकता है या नहीं। हमें अपना कार्यक्रम इस मान्यता पर आधारित नहीं करना चाहिए कि निकट भविष्य में ही बेरोजगारी के परिणाम में कमी नहीं होगी। फिलहाल उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री की पूर्ति करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम को उस दिशा में अवरोधक नहीं बनना चाहिए।

यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत की अर्थ-व्यवस्था इस वक्त एक संघर्ष से होकर गुजर रही है। संघर्ष है उच्च उत्पादन खर्च और वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति से। इन दोनों बातों से ही ऊँची कीमतों को प्रश्रय मिलता है। इसका परिणाम होता है रहन-सहन का मँहगा हो जाना। उच्च उत्पादन लागत का एक कारण है बेरोजगारी या अल्प-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को काम प्राप्त कराने की आवश्यकता। इसके लिए पूँजी-प्रधान उद्योगों के समक्ष श्रम-प्रधान उद्योग कार्यक्रम है। पूँजी-प्रधान उद्योग सस्ती कीमत पर सामान मुँहैया कर सकते हैं, लेकिन श्रम-प्रधान उद्योगों का सहज अर्थ है अपेक्षाकृत अधिक लागत।

आर्थिक दृष्टि से प्राणवान

द्वितीय योजना-काल में भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योगों पर ८७ करोड़ से कुछ अधिक रुपये खर्च किये। इनमें से ६८ करोड़ ६८ लाख रुपये अकेली खादी पर खर्च हुए। तृतीय योजना में खादी व ग्रामोद्योगों के लिए ९२ करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह एक बड़ा निवेश है। जैसा कि कमीशन के अनुक्रमिक

वर्षों के प्रतिवेदनो से पता चलता है, इस निवेश से उत्पादन भी प्रायः उसके बराबर ही होगा। इसमें अन्य उत्पादनों के कुल लागत खर्च और सरकार की करावान नीति पर भी प्रभाव पड़ता है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि खादी में निष्ठा रखनेवाले हमारे बुजुर्ग नेतागण धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, नये व्यक्तियों का कार्यक्रम के साथ उनके समान ही भावात्मक लगाव नहीं होगा। इसलिए अब वह समय है कि कार्यक्रम को आर्थिक दृष्टि में प्राणवान आधार पर प्रतिष्ठापित किया जाय।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं खादी और ग्रामोद्योगों का कार्यक्रम सरकार ने मात्र राष्ट्र पिताकी देन के रूप में हाथ में नहीं लिया बल्कि हमारे सर्वाधिक गरीब वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के उपाय के रूप में भी। अब इस बात का निर्णय करना है कि राष्ट्र के सर्वाधिक गरीब वर्ग को यह कार्यक्रम कहाँ तक राहत पहुँचाने में समर्थ हुआ है। कोई यह कह सकता है कि न केवल समग्र राष्ट्र, बल्कि सबसे गरीब वर्ग के भी सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर खादी व ग्रामोद्योगों का इतना प्रभाव नहीं पड़ा है कि उससे तृतीय योजना के पाँच वर्ष में उन पर ९२ करोड़ रुपये खर्च करने का औचित्य सिद्ध हो। बड़े उद्योगों के हिमायती कह सकते हैं कि इन ९२ करोड़ रुपये की लागत से उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन करने के लिए सरकार कुछ कपड़ा मिले

तथा कारखाने स्थापित कर सकती है। फिलहाल कपड़े और अन्य उपभोक्ता सामग्री की जो कमी है, उसमें कीमते बढ़ी हैं। उपभोक्ता सामग्री की कीमते बढ़ना सरकार के लिए गम्भीर समस्या है। उपभोक्ता सामग्री की कमी दूर करने और फलस्वरूप उनकी कीमते कम करने के लिए, कोई कह सकता है कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उसे ऐसे कार्यक्रम में इतनी बड़ी रकम रोकनी चाहिए, जहाँ उत्पादन अपेक्षाकृत कम होगा, और क्या अपेक्षाकृत अधिक फलप्रद विनियोजन करके उपभोक्ता सामग्री की कमी दूर करने में सहायता नहीं करनी चाहिए।

कमीशन तथा खादी व ग्रामोद्योगों के समर्थकों को इस सम्बन्ध में विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इन कार्यक्रमों से उपभोक्ता सामग्री—ज्याम करके ग्रामीणों की कपड़े सम्बन्धी—की कमी दूर करने में वास्तव में काफी सहायता मिलेगी। न केवल स्थापित उद्योग वरन् समग्र कार्यक्रम आर्थिक दृष्टि से प्राणवान हो, इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारी जनता के सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए यह कार्यक्रम है। जनता की विकासोन्मुख उच्चाकाक्षाओं के अनुसार ये व्यक्ति भी अपना जीवन-यापन कर सकें, वैसे ही रह सकें, उनके साथ कदम मिला कर चल सकें—ये सब सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

नयी दिल्ली ७ सितम्बर १९६३

कर्म युग में अधभक्ति बिल्कुल बेकाम है, प्रायः आकुल करनेवाला है और उतना ही दुःखदायी भी।

—महात्मा गांधी

खादी किस ओर ?

ध्वजा प्रसाद साहू

विस्तृत पैमाने पर खादी कार्य का विस्तार करने के लिए जन-बल तैयार करना होगा। जनता को इसके विकास का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेने के लिए प्रोत्साहित करके यह काम हो सकता है। मुफ्त बुनाई का नया प्रस्ताव और ग्राम इकाई कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपना पुरुषार्थ दिखाने का अवसर प्रस्तुत करते हैं।

पिछले महीने श्री गांधी आश्रम का वार्षिक अधिवेशन अकबरपुर (जिला फैजाबाद) में हुआ था। आश्रम की ओर से जो प्रतिवेदन पेश किया गया उससे प्रकट हुआ कि पिछले वर्ष के लिए खादी उत्पादन और बिक्री का जितना अनुमान किया गया था, वह पूरा हुआ। फिर भी, अगले वर्ष का जो अन्दाजा लगाया गया था, उसमें काम बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं था। सारे देश की खादी सस्थाओं का प्रायः यही हाल है। पुरानी बड़ी-बड़ी सस्थाओं की शक्ति सीमा पर पहुँच गयी है और वे काम बढ़ाना नहीं चाहती। नयी सस्थाओं के पास कार्यक्षम कार्यकर्ताओं का अभाव रहता है, खादी बिक्री की परेशानी रहती ही है, इसलिए उनके काम नहीं बढ़ते। कम्बलो के उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि हुई है, जिन्हे सेना के इस्तेमाल के लिए सस्थाएँ बनाती हैं। सूती खादी का उत्पादन बड़ी धीमी गति से कहीं-कहीं बढ़ रहा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि खादी उत्पादन की गति ठिठक-सी गयी है। इस स्थिति में खादी की गति को देख कर इसके भविष्य के बारे में चिन्ता होती है। कहावत है जो लडका न बढ़ता है और न मोटा होता है वह मर जाता है। तो क्या खादी का भी वही हाल होनेवाला है ?

रिबेट कोई हल नहीं

खादी सस्थाओं के बहुत-से जिम्मेवार व्यक्तियों की यह राय है कि आज जो प्रति रुपया बीस नया पैसा रिबेट दिया जाता है, उसको क्रमशः बढ़ाते जाना चाहिए,

जिससे खादी सस्ती हो और उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह सोचने की बात है कि जब मिल के कपड़े से खादी का दाम दुगुना-तिगुना और उससे भी ज्यादा है तो रिबेट बढ़ाते जाने से क्या खादी स्थायी बन सकती है और क्या सरकार को इतनी रकम देने के लिये तैयार किया जा सकता है ? मैं समझता हूँ कि जब तक बुनियादी दृष्टि से इस पर विचार नहीं किया जायेगा, तब तक चाहे जितनी भी रिबेट की रकम बढ़ाई जाय—जिसकी प्राप्ति की बहुत कम सम्भावना है—खादी की जड़ मजबूत नहीं बन सकती। खादी के लिए आज जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित है। इस पर खादी प्रेमियों को गभीरता से विचार करना चाहिए और मजबूती के साथ ठोस तथा क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिए।

मुफ्त बुनाई

खादी का विकास आज जिस मद गति से हो रहा है उससे आचार्य विनोबा भावे को सतोष नहीं है और वे यह अनुभव करते हैं कि बिना क्रान्तिकारी कदम उठाये खादी को जीवित नहीं रखा जा सकता। इसीलिए वे खादी सस्थाओं को रिबेट छोड़ने के लिये सलाह दे रहे हैं। पड़ोसी के लिये त्याग करने की भावना यानी 'पड़ोसी धर्म' के पालन पर ही खादी टिक सकती है। इसे जिन्दा रखने के लिए वही भावना एक मात्र इसका सहारा हो सकती है। नवद्वीप में विनोबाजी के सम्मुख खादी सस्थाओं के प्रतिनिधियों ने रिबेट छोड़ने की तत्परता बुनाई सहायता देने की शर्त पर दिखलाई। विनोबाजी ने

मध्यम मार्ग समझ कर उसे मजूर किया। उसमें उन्हें दीख पड़ा कि खादी की प्रगति पर्याप्त मात्रा में हो सकेगी। वे मानते हैं कि बुनाई सहायता से खादी व्यापक बन सकती है और व्यापकता से शक्ति पैदा होगी। आज की खादी अपने अथवा जनता के बल पर नहीं चल रही है। खादी आज बापू के पुण्यार्थ और सरकार की कृपा से चल रही है। खादी के प्रसार के लिए जनता की शक्ति का आवाहन करना होगा। इसके लिए सस्थाओं का स्वरूप बदलना होगा, जिसके लिए सस्थाओं के पास काफी जन-बल है। आवश्यकता है सस्थाओं के संचालक खादी के काम को जनता के हाथ दे देने, सौंपने का सकल्प करे और उनके लिए तैयारी करे। बुनाई सहायता पुरुषार्थ करने का काफी मौका दे रही है।

कार्यकर्त्ताओं की भूमिका

आज देश में हजारों सस्थाओं द्वारा करीब एक लाख गाँवों में खादी का काम हो रहा है। कुल मिला कर ३०-३५ हजार खादी कार्यकर्त्ता सारे देश में फैले हुए हैं। मेरा अन्दाज है कि इनमें से २०-२५ हजार कार्यकर्त्ता ऐसे निकल सकते हैं जो एक-एक करके पांच हजार आबादीवाली एक-एक पंचायत में सघन रूप से चर्खों का प्रचार कर सकते हैं और खादी का विचार जनता को समझा कर जो खादी गाँव में बनेगी उसका अधिकांश हिस्सा वहीं खर्च हो, इसकी दीक्षा दे सकते हैं। गाँव में उद्योग देकर बेकारी निवारण करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की है, यह समझाना आवश्यक होगा। पंचायत स्तर पर सस्था खड़ी हो और उसकी जिम्मेवारी गाँव के लोग ले, इस भावना से खादी कार्यकर्त्ताओं को काम करना होगा। जिन बीस-पच्चीस हजार कार्यकर्त्ताओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनमें से बहुत-से लोग गाँवों के रहनेवाले होंगे। वे अपनी-अपनी पंचायतों की जिम्मेवारी ले सकते हैं और अबोस-पडोस के गाँवों में अपने उदाहरण से वातावरण बना सकते हैं। जन-शक्ति को जगाने और उसे संगठित करने के दूसरे कारगर उपाय भी सोचे जा

सकते हैं। मैंने जो सुझाव दिये हैं, वे थोड़े-बहुत अनुभव के आधार पर दिये हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में आज की स्थिति को कायम रखना खादी के विकास के लिए घातक होगा। हम लोगों को सोचना होगा कि खादी को जनता का बल किस प्रकार प्राप्त हो।

कमीशन का ग्राम इकाई कार्यक्रम इस दिशा में जाने का एक ठोस कदम है। यद्यपि इकाइयों का लक्ष्य बहुत ऊँचा रखा गया है, जहाँ तक पहुँचने में काफी समय की आवश्यकता है। फिर भी, प्रारम्भ में प्रगति का जो मापदण्ड इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है वह केवल इकाई के अन्दर रहनेवाले प्रति व्यक्ति एक गज खादी के इस्तेमाल का ही है। नयी इकाइयों में इस छोटे-से कार्यक्रम को भी पूरा करने में समय लगेगा। उसे प्रत्येक खादी सस्था अपने उत्पादन केन्द्र के गाँवों में आसानी से पूरा करती हुई जनता को जिम्मेवारी उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

जहाँ कताई, वही बुनाई

बुनाई की छूट से सस्थाओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी इस बात की आ जाती है कि जहाँ कताई हो वहाँ बुनाई का भी प्रबन्ध किया जाय। यह काम कठिन अवश्य है, पर दुसाध्य नहीं। जहाँ पेशेवर बुनकर हैं, वहाँ यह आसान है। लेकिन जहाँ पर पेशेवर बुनकर नहीं हैं, वहाँ पर नये व्यक्तियों को बुनाई का काम सिखाना होगा। पहले का अनुभव यह रहा है कि जिन लोगों ने यह काम सीखा उन्होंने इसे अपना पेशा नहीं बनाया। इससे बहुत लोगों को शका होती है कि यह कार्यक्रम सफल होगा या नहीं। इसके विपरीत दूसरा भी अनुभव है कि कई लोगों ने यह काम सीखा और वे अच्छी तरह से उसे (बुनाई) कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना होगा जिनको काम की भूख हो। बिना भूख के काम लाने से असफलता ही हाथ लगती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हजारों अम्बर चरखों का बैठ जाना है। कठिनाइयाँ अनेक हैं, लेकिन साथ ही पुरुषार्थी आदमी को कोई भी कठिनाई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

पटना २० अगस्त १९६३

खादी का भविष्य

रामकृष्णराव कृ. पाटिल

खादी जब तक समुदाय के जीवन का अविभाज्य अंग नहीं बन जाती, तब तक वह जीवित नहीं रह सकती। व्यापारिक खादी के लिए बहुत ही सीमित क्षेत्र है।

खादी-कार्य के पीछे अतत क्या उद्देश्य है? क्या इसका उपयोग जीवन के नये मूल्यों को लेकर नये समाज की रचना करने के साधन के रूप में किया जाने-वाला है अथवा जरूरतमंद लोगों को रोजगारी, खासकर सहायक धधा, मुहैया करने के रूप में ही इसका उपयोग है? इस कार्य सम्बन्धी स्पष्ट धारणा का अभाव ही भ्रम उत्पन्न करने और खादी कार्यकर्ताओं के बीच के मतवैभिन्य के लिए भी जिम्मेवार है। निरुत्तर हो जाने पर उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि उनका उद्देश्य तो रोजगारी या सहायक धधे के रूप में खादी-कार्य करने का है, खादी को नये समाज के नये मूल्यों का वाहक बनाने की जिम्मेवारी अखिल भारत सर्व सेवा सघ या दूसरी सस्थाएँ उठाये। परतु इस तरह जो लोग दलील करते हैं, वे यह महसूस नहीं करते कि इस दृष्टि से तो वे गाधीजी के नाम का उपयोग करने और इस प्रकार से व्याख्यित खादी के साथ उस नाम को जोड़ने के हकदार नहीं हो सकते।

नव संस्करण

प्रारभ में सन १९२० से १९२९ के काल में जब खादी-कार्य आरभ हुआ, गाधीजी की इस काम के पीछे जो भी दृष्टि रही हो, बाद में, सन् १९४० के पश्चात् जब उन्होंने खादी कार्य का नवसंस्करण किया, तब उनके सामने खादी सबधी लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। जब उन्होंने कहा कि “कातो, समझ बूझ कर कातो, जो काते वह पहने और जो पहने वह काते ” आदि, तो यह बात स्पष्ट थी कि खादी में सम्बन्धित

नयी दृष्टि के बारे में उनका मतव्य क्या है। वे चाहते थे कि शातिमय सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में खादी-कार्य किया जाय, जो हमें अहिसक अर्थात् शोषण-रहित समाज की स्थापना की दिशा में अग्रसर करेगा। यही मूल है और जो खादी कार्यकर्ता पूर्ववत् खादी कार्य जारी रखना चाहते हैं, वे शीघ्रातिशीघ्र इस बुनियादी बात को समझ ले। तब न सिर्फ वे अपनी अन्तर्निहित कमजोरी का अनुभव कर सकेंगे, बल्कि कदाचित वे बैकल्पिक उद्देश्य के सबध में विचार करने और उसको परखने की ओर भी प्रवृत्त हो सकेंगे।

मूल्यांकन समिति का दृष्टिकोण

जब खादी की मूल्यांकन समिति ने खादी कार्य की प्रगति के बारे में अपना विवरण पेश किया, और कुछ आलोचकों की राय में खादी के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में हुई भारी प्रगति के लिए खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा खादी कार्यकर्ताओं को यथोचित श्रेय देने में वह असफल रही तो मौजूदा उपलब्धियों पर निर्णय देने की बनिस्वत उसे (समिति को) खादी काम के भविष्य के बारे में ही विशेष रूप से अपनी राय प्रकट करनी थी। उसकी मुख्य आलोचना यह थी कि खादी-कार्य एक तो कुछ पम्परागत क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया है और दूसरे, वहाँ भी ग्रामीण समाज के जीवन से वह एकरूप नहीं हो सका है। उसने अनुभव किया कि खादी का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब वह ग्राम जीवन से पूर्णत एकरूप हो जाय। यही मत पूसा सम्मेलन द्वारा प्रकट किये गये वक्तव्य में भी स्वीकार किया गया। उसमें कहा गया कि खादी-कार्य को नया

मोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि उसमें बुनियादी बातों का समाधान हो सके। इसीलिए ग्राम इकाई का कार्यक्रम बना और वर्तमान खादी-कार्य सघन रूप से स्थापित ग्राम इकाइयों को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया।

उद्देश्यों से सम्बन्धित इन दृष्टि भेदों के बारे में अब मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि जिनके मन सदिग्धता-स्थिति में है, उन्हें भी यदि यह कहा जाय कि जैसा काम आज वे कर रहे हैं, उसमें वे गांधीजी के नाम का उपयोग तो नहीं कर सकते, तो इसमें वे कुछ तथ्य ही अनुभव कर सकेंगे। परन्तु नये उद्देश्यों की हार्दिक स्वीकृति भी विशेष उपयोगी तब तक नहीं बन सकती, जब तक इस बात की स्पष्ट अनुभूति न हो जाये कि इस नये दृष्टिकोण की उपलब्धि के लिए खादी कार्य का पुनरुत्थान किस प्रकार में होना चाहिए। नया समाज क्या है और उसके नये मूल्य कौन से हैं? इस नये समाज में शोषण नहीं होगा और नये मूल्य वे हैं, जिनके अनुसार सामाजिक रूप में उपयोगी सभी कार्यों का पारिश्रमिक समान या करीब-करीब समान होना चाहिए, ताकि इस समाज के सदस्य अन्य लोगों की तरह ही रह सकें। अर्थात्, अन्नोत्पादन, वस्त्रोत्पादन, तेल-उत्पादन, बढई-गिरी, लुहारी आदि कामों में समान रूप से पारिश्रमिक दिया जाय, क्योंकि ये सभी काम समाज-जीवन बनाये रखने की दृष्टि से समान रूप से आवश्यक हैं। “उपयोग के लिए उत्पादन” का सही अर्थ यही है।

ग्रामदान के साथ सम्बंध

एक समाज अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करता है और जो लोग उत्पादन करते हैं, वे उसमें हिस्सा बँटाते हैं। इससे कुछ निष्कर्ष पर आना पड़ता है। सर्वप्रथम, सबसे सामाजिक भावना होनी चाहिए। इसीलिए, पश्चिम बंगाल के नवद्वीप स्थान में खादी कार्यकर्त्ताओं के सामने बोलते हुए विनोबाजी ने अपने भाषण में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि खादी कार्य का तब तक कोई भविष्य नहीं है, जब तक कि वह खेती के साथ न जुड़ जाय। खादी का अर्थ केवल रोजी के लिए

कताई या स्थानीय रूप से कपड़े का उत्पादन और खपत नहीं है। प्राथमिक रूप से वह समाज द्वारा अपने निज के उपयोगके लिए किया हुआ वस्त्रोत्पादन है। यह विचार अमल में लाने की दृष्टि से जरूरी है कि समाज के मुख्य साधन-स्रोत समुदाय के ही पास हों। अब, जब तक कि मनुष्य के पास उसकी अपनी भूमि है, वह समाज के विरुद्ध भी उसे अपने पास रखता है। परन्तु एक बार समाज को भूमि दे देने के बाद वह समाज के लिए ही उसकी देखभाल करता है। वस्तुतः फिर यह बात कोई खास महत्व की नहीं रह जाती है कि दान के पहले एव पश्चात् उसकी भूमि-सीमा में क्या परिवर्तन होता है और किस हद तक वह अपनी जमीन में दूसरों के साथ हिस्सा बँटाता है। अगर, वह ऐसा नहीं भी करता है, तो भी यह तथ्य कि अब वह समाज के लिए भूमि रखता है, उसके दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन ला देता है। पहले वह ‘अपनी’ भूमि जोतता था। अब वह समाज की भूमि को जोतता है। अब भी उसके अपने लिए भूमि की जुताई तो जारी ही है, परन्तु जैसा कि विनोबाजी बारबार कहते हैं, समाज को भूमि-दान करना ही अपने आप में एक ऐसी सामाजिक चेतना जागृत करा देता है, जिसको और भी आगे विकसित करते रहना आवश्यक है। इसीलिए वे इस बात पर जोर देते हैं कि ग्रामदानी गाँवों में खादी कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू हो जाना चाहिए। और, यदि वह अन्यत्र भी चल रहा हो, तो वहाँ भी उसे बद नहीं करना चाहिए। परन्तु आवश्यकता केवल इस बात की है कि कार्यकर्त्ता यह समझे कि वह कार्य सिर्फ अपने बल पर नहीं टिक सकता और देर-अबेर उसे भूदान-आधारित होना ही है। अतः व्यवहार में खादी-कार्य को भूदान और ग्रामदान और भूदान-ग्रामदान को खादी के प्रचार के साथ-साथ चलना ही होगा।

अल्प उपयोगार्थ उत्पादन

समाज का अपने निज के उपभोग के लिए वस्त्रोत्पादन ही इस बात की एकमात्र गारंटी है कि उसकी उत्पादन की लागत के बारे में बहुत अधिक सतर्कता बरते

बिनाभीयह कार्य सतत जारी रह सकता है। एव केवल इन्ही परिस्थितियों में ही यह खुले बाजार में मिल कपड़े की प्रतिस्पर्धा में खड़ा रह सकता है। कोई भी किसान अपने घर में उत्पादित चावल या गेहूँ की लागत देखने नहीं बैठता। इसी तरह, जहाँ समाज ने अपना कपड़ा खुद बनाना तय किया कि वह स्वाभाविक रूप से उसके पास उपलब्ध सभी उच्चतम कुशल साधनों से लाभ उठाएगा, परंतु इसके उपरांत, वह इस बात की फिक्र नहीं करेगा कि इन वस्त्रों के उत्पादन की लागत क्या आती है और इन कपड़ों का बाजार-भाव क्या है। जैसा कि स्वर्गीय डॉ. जे. सी. कुमारप्पा अक्सर कहा करते थे, 'हम जब हलुवा खाना चाहते हैं, तो हम उसे तैयार करके खा लेते हैं। हम यह नहीं देखने जाते कि उस पर हमें क्या लागत बैठी और न हम यही तुलना करते हैं कि बाजार से यह हमें किस कीमत पर प्राप्त हो सकता था।'

काल्पनिक जगत

समाज द्वारा निर्मित कपड़े के उत्पादन के बारे में भी यही स्थिति आनी चाहिए। यहाँ फिर समाज का ही निर्णय महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल उन परिस्थितियों में ही, जिनमें समाज यह तय करता है कि अपने लिए वह अन्न और वस्त्र का उपयोग करेगा, इस तरह का तरीका उपयोगी हो सकता है। समाज का इस प्रकार का निर्णय कार्यरूप में तभी आ सकता है, जब श्रम-विभाजन के सिद्धांत का अनुसरण किया जाय। समाज में कुछ लोग अन्नोत्पादन करेंगे, तो कुछ लोग वस्त्रोत्पादन करेंगे। दूसरे कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनायेंगे। ऐसे यह प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु चूँकि कुम्हार को अन्न-वस्त्र की जरूरत है और किसान को बर्तन और कपड़ों की तथा बुनकर को अनाज और बर्तन की, इसलिए सबका उत्पादन हरेक अपनी आवश्यकतानुसार पायेगा। यह व्यवहार में, वस्तुओं के आदान-प्रदान के रूप में भी चल सकेगा या पारिश्रमिक तय करके मुद्रा-विनिमय के रूप में भी। आलस्य और निष्ठलेपन को रोकने के लिए उत्पादन की मात्रा के साथ पारिश्रमिक को जोड़ना होगा।

लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि समाज के भीतर, समाज द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की व्यवस्था होगी।

इसका अर्थ होता है, व्यक्ति के पारिवारिक जीवन का ऐसा विस्तार, जिसमें समस्त ग्राम-समुदाय समाविष्ट हो जाय। पर क्या यह कभी संभव भी है? और अगर यह संभव है, तो इसमें और सामूहिक (कलेक्टिव) जीवन के बीच क्या अंतर रहेगा? पहले प्रश्न का उत्तर निश्चयात्मक रूप से देना जरा कठिन है। ऐसे कुछ गाँवों की ओर, जहाँ ग्रामदान के पश्चात् इस प्रकार घटित हुआ है संकेत करके ही इसकी मिसाल दी जा सकती है। इन गाँवों में तो यहाँ तक देखा गया है कि ग्राम समुदाय के वे सदस्य, जिन्हें गाँव के बाहर रोजगारी प्राप्त थी, उन्होंने अपने ग्राम-समुदाय द्वारा निर्धारित वेतन स्वीकार किया और अपनी उस आय की शेष रकम ग्राम-समुदाय को अर्पित कर दी। यह सब कुछ काल्पनिक या अव्यावहारिक दिखाई दे सकता है। एक अर्थ में यह ऐसा है भी।

इजरायल में ऐसी ही करीब ३०० बस्तियाँ अपने आर्थिक जीवन का उत्तरोत्तर विकास करती जा रही हैं और वे गत ४० वर्षों से वहाँ विद्यमान हैं। इस कार्य की पृष्ठभूमि में जो आदर्शवादिता है, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु यह उदाहरण इस बात की ओर संकेत करता है कि अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग हो रहे हैं। आदर्शवादिता के दृष्टिकोण से सभी परिवर्तन—मुख्यतया सामाजिक और आर्थिक संगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन—हमेशा आदर्शवादी ही दिखाई देते हैं, खासकर उन लोगों को, जिनके दिमाग नये अपेक्षित परिवर्तनों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस अर्थ में, भूदान, ग्रामदान और ऐसे ही अन्य नये परिवर्तन, जैसे कि सहकारी खेती का कार्यक्रम, आदर्शवादी महसूस हो सकते हैं। परंतु सिर्फ इसी कारण उद्देश्य को तो नहीं छोड़ देना चाहिए।

इच्छा स्वातंत्र्य

पर स्पष्टतया ऐसे समुदाय (कम्युनिटी) में और सामूहिकता (कलेक्टिव) में अन्तर होगा। दोनों में समानता

इतनी ही है कि दोनों में ही व्यक्ति सामाजिक नियम-व्यवस्था, खासकर अपने आर्थिक जीवन के नियम, स्वीकार करता है। परन्तु व्यक्ति द्वारा उसकी स्वैच्छापूर्वक स्वीकृति के अलावा, समुदाय अपना आर्थिक जीवन अपने इच्छानुसार, आयोजित करने में भी स्वतंत्र रहगा, जो कि सामूहिकता से सर्वथा भिन्न होगा, जो 'राज्य' के नाम से पहचाने जानेवाले विशाल समुदाय के लाभ के विचार से ही नियंत्रित होता है। अर्थात् उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि समुदाय के हित तथा क्रिया-कलाप सदैव राज्य के हितों व क्रिया-कलाप से विपरीत होंगे। फिर भी, समुदाय मुक्त व्यवसाय के विचार में माग-दर्शित होकर अपने उत्पादन और खपत का आयोजन खुद करने में स्वतंत्र होगा।

दोषपूर्ण आयोजन

कुछ खादी-कार्यकर्ताओं का मत है कि अम्बर चरखे के आगमन ने खादी तकनीक में ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है कि अब खादी का उत्पादन और बिक्री वट्टे पैमाने पर हो सकेगी। पर यह दृष्टिकोण खादी के बृहत् उत्पादन और बिक्री के विचार पर अधिक आधारित है, न कि समुदाय के जीवन के साथ खादी को एकात्म करने के विचार पर। इस पर भी इस दावे में बहुत अतिशयोक्ति है और, इस धारणा को अंगीकार करने के फलस्वरूप ही, दोषपूर्ण आयोजन हुए है। खादी-कार्य के लिए इससे बढ़कर क्लेशकारी और नैतिक अवनति की बात और क्या हो सकती है कि विशाल संख्या में अम्बर चरखे उत्पादन केंद्रों में बेकार पड़े हैं।* शायद ही भविष्य में उनका उपयोग ठीक से हो सकेगा और संभवतः रद्दी माल के रूप में वह बेच देना होगा। अम्बर चरखा यद्यपि अधिक रोजगारी दे सकता है और खादी

की कीमत बढ़ा सकता है, फिर भी अम्बर खादी और मिल के सामान्य कपड़े के दाम में अब भी उन्ना अधिक अंतर है कि एक अनिवार्य मर्यादा के पश्चात् संभवतः वह बाजार में नहीं खपायी जा सकेगी। और, इस धारणा की भी, कि अम्बर चरखे का काम बढ़ाने से कताई द्वारा काफी हद तक रोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है, कुछ सीमाएं स्पष्ट हैं। अम्बर चरखे तक पहुंच जाने मात्र में कताई को पूरक रोजगारी देनेवाले धंधे की स्थिति पर से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसका बाजार में लाने के लिए अभी भी राज्य की सहायता अपेक्षित रहेगी।

केवल कताई से नहीं

और जब कि पन्थर स्वस्थ व्यक्ति का रोजगारी देने की जिम्मेदारी राज्य की मान ली गयी है, तब ऐसी रोजगारी केवल कताई के जरूरतों दी जानी चाहिए, ऐसा कहना एक मर्त्य या भिन्न बात होगी। राज्य के पास रोजगारी मुहैया करने के अलग-अलग कई क्षेत्र हैं। वह उस बात पर जोर दे सकता है कि जहाँ तक सारे स्वस्थ लोगों का संबंध है, अन्य सभी उपायों का पूरा उपयोग ले लेने के पश्चात् ही, कताई रूपी साधन का उपयोग रोजगारी के लिए किया जा सकता है। अतएव यह शर्त, कि अम्बर चरखे पर कता सभी सूत सरकार को ऐसे दामों पर खरीद ही लेना चाहिए कि जिनमें सूतकारों को पूरा जीवन वेतन मिल जाय, सरकार द्वारा तभी स्वीकार की जा सकती है, जब ऊपर बतायी हुई स्थिति आ जाय। अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनिवार्य हो जाता है कि खादी-कार्य कमोबेश ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का स्थायी अंग तभी और केवल तभी बना रह सकता है, जब हर ग्रामीण समुदाय यह स्वीकार

* पिछले दो वर्षों में, जितना संभव हो सका, कमीशन ने इन बेकार पड़े अम्बर चरखों में से अधिकतम चरखे चालू करने की दृष्टि से कई कदम उठाये हैं। अन्य योजनाओं के साथ-साथ उस योजना का भी उल्लेख यहां कर देना उचित होगा, जिसके अनुसार अम्बर चरखों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के साथ उन्हें हलका बनाने के भी प्रयत्न किये गये हैं और जहाँ सूतकारों द्वारा

अधिक घंटों तक सूत कानने की शक्ति हो, वहां मौजूदा ४ तकुओं के अम्बर चरखों का रूपान्तर ६ तकुओंवाले चरखों में भी किया जाता है। दिनांक ३१ जुलाई १९६३ तक कमीशन ने ऐसे २६,७०५ चरखों का नवीनीकरण कर दिया है और १०,५०६ का तैयार होने की दृष्टि से प्रयत्न किया जा रहा है।

—सम्पादक

कर ले कि चरखा एक ऐसा साधन है, जो उसे वस्त्र दे सकता है और इसलिए वह उसे ग्राम समाज की अन्य आर्थिक प्रवृत्तियों में मिला लेता है।

खादी के उद्देश्य

कुछ विचार करने पर यह दिखाई देगा कि ऐसी एकरूपता या समग्रता चालू पारिवारिक अर्थ-व्यवस्था के स्थान पर सामुदायिक अर्थ-व्यवस्था की स्थापना का निर्देश करती है। उत्पादन और वितरण की व्यवस्था अन्य समुदाय द्वारा ही आयोजित होनी चाहिए, न कि आज की तरह व्यक्तिगत रूप से। खादी-कार्य को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का स्थायी अंग बनाने के पूर्व उपर्युक्त परिवर्तन ग्रामवासियों के मानस में लाना होगा। ऐसा ही उत्पादन राज्य की सहायता के बिना अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है, जबकि केवल रोजगारी देनेवाली खादी अपने अस्तित्व के लिए राज्य की सहायता पर और महात्मा गांधी द्वारा इसके लिए किये गये पुराने प्रयत्नों पर ही निर्भर रहती है। ये दो स्थितियाँ जब तक रहेगी, तब तक ही खादी टिक सकेगी।

उत्पादन और बिक्री में अस्थायी वृद्धि हो जाने और खादी भंडारों के स्थान पर खादी भवन बन जाने से ही खादी कार्यकर्त्ताओं को अपनी कार्यप्रति की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। खादी-कार्य के मूल उद्देश्य की यह पूर्णता नहीं है, वह तो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, नये मूल्यों सहित नये समाज के निर्माण करने का कार्य है। महात्मा गांधी का यही स्वप्न था, जो अब तक अपूर्ण रहा है। ऐसे कुछ क्षेत्र, जहाँ समुदाय ने खादी को अपना वस्त्रभरण पूरा करने के एक साधन के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर अपने ग्रामीण जीवन के साथ उसे एकरूप बना लिया है, खादी के आदर्श को अधिक अच्छी तरह प्रचारित कर सकेगे, न कि कृत्रिमता से बढ़ा हुआ उत्पादन और करोड़ों रुपये की खादी की बिक्री। इसमें तो खादी कार्यकर्त्ताओं में स्वार्थों की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी है। और जो मूलभूत उद्देश्य उनके सामने सतत रहना चाहिए था, उसके बारे में उनमें सभ्राति पैदा हो गयी है।

नागपुर १८ जुलाई १९६३

हमारे आनन्द और अववाद सही मानी में ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जो कि, राजनीतिक इतिहास में कितने भी छोटे क्यों न हों, सामूहिक रूप से भविष्य के परीक्षण हेतु अत्यावश्यक हैं। अधिकारों के कार्यकारी सिद्धान्त का अर्थ है कि हमें अधिकार दिये जाते हैं ताकि हम अपनी सामाजिक विरासत में और अभिवृद्धि करें। हमें पाने का नहीं, करने का अधिकार है। माना कि हमारा समाज कल्याण कोष में योगदान कम अथवा अधिक होगा, फिर भी योगदान के माध्यम तो रहेंगे ही।

-हैरोल्ड जे लास्की : ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स

खादी का मिशन

झवेरभाई पटेल

खादी अपने वर्तमान रूप में हमारी अर्थ-व्यवस्था की बुनियादी और आवश्यक समस्याओं को हल करने में असफल रही है। विनोबाजी इसे अकाली खादी कहते हैं। खादी कार्य का सगठन इस रूप में किया जाना चाहिए कि उससे कारीगरों का ज्ञान, शक्ति और चैतन्य बढ़े। ऐसा अस्तित्व के लिए उनके सर्प को कम करके ही किया जा सकता है। हमारे गाँवों को भी बड़ी और प्राणवान आकार की कार्यकारी इकाइयों में पुनर्गठित करना होगा ताकि ग्रामीणों का दृष्टिकोण व्यापक बने और उन्हें विकास के अवसर प्राप्त हो।

अब वह समय आ गया है जब खादी के सिद्धान्त पर फिर से रोशनी डाली जाय। सन् १९४७ में गांधीजी ने कहा था “बहुत-से रचनात्मक कार्यों पर अब तक राजनीति से अलग रह कर अमल किया जाता रहा है। कांग्रेस के हुकूमत में आने के बाद, मन्त्रीगण अगर चाहते तो अपने अनुभवों (रचनात्मक कार्यकर्ता की हैसियत से) का फायदा उठा सकते थे और अब तक जो कुछ वे प्रयोग के रूप में करते रहे, उसे मुक्त भर में फैला सकते थे।” दो पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में खादी कार्यक्रम को अमल में लाने का हमने १० साल से ऊपर का तजुर्बा हासिल किया है और अब हम इस स्थिति में आ गये हैं कि इस बात की जाँच कर सके कि खादी के मिशन को पूरा करने में यह कार्यक्रम कहाँ तक प्रगति कर सका है अथवा सही दिशा में चल भी रहा है या नहीं।

खादी का असल मिशन क्या है? खादी की ‘श्रुति’ और ‘स्मृति’ क्या है? क्या समय-समय पर खादी कार्यक्रम इस मिशन की रोशनी में बनाये और मूल्यांकित किये जाते हैं?

अधूरा विचार

गांधीजी ने खादी की श्रुति की व्याख्या एक स्पष्ट सूत्र में की है—खादी कपड़ा नहीं, विचार है। स्पष्टतः, अपने समय की स्थिति की सीमाओं के अन्दर वे अपने सूत्र की पेचिदगियों की पूरी गणना नहीं बैठा सके।

उस समय के हालात के मुताबिक वे सिर्फ सीबी-सादी उत्पादन-तक्नीक ओर किसी रूप में सगठन खड़ा करने का पहला कदम ही उठा सके।* गांधीजी का खयाल था कि एक कदम ही उनके लिए काफी है। इसमें कोई शक नहीं कि पहला कदम काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन वह आखिरी कदम नहीं था—यहाँ तक कि बिचला कदम भी नहीं था। ये कदम काफी खोज और तजुर्बे के जरिये उठाये जाने चाहिए थे। पर ऐसा लगता है कि हम पहले कदम से ही चिपटे हुए रहने की कोशिश में लगे हैं और नये तजुर्बे करने की हम में हिम्मत नहीं है। मौजूदा अवस्था की सबसे बड़ी वजह यह है कि खादी के मूल्य या मूल्यों को उस सामाजिक ढाँचे के सन्दर्भ में पूर्ण स्वरूप देना अब भी शेष है जो उन मूल्यों को कायम और जिन्दा रख सके। विचार अधूरा होने के कारण आगे के कदम असम्भव हो जाते हैं और स्वभावतः समूचा खादी कार्यक्रम उस प्रथम कदम की रोशनी में ही बनाया जा रहा है, जो गांधीजी ने उठाया था। इस वजह से खादी-आन्दोलन का आगे बढ़ना रुक-सा जाता है। इसलिए विचार को पूर्ण स्वरूप देना अर्थात् ‘पूर्ण पद्म्यत् मा अंशम्’ की स्थिति प्राप्त करना खादी आन्दोलन की बुनियादी जरूरत हो गयी है।

“आज का इन्सान एक धोखा खाया हुआ इन्सान

* गांधीजी ने एक कार्यक्षम चरखे की ईजाद के लिए एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

है—उसे बहुत-से ऐसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और तकनीकी पुरोहितों ने धोखा दिया है जिनमें हर एक अपने धंधे का उस्ताद और कूप मण्डूक बना हुआ है।”*

कार्यकर्त्ताओं तक ही सीमित

खादी आन्दोलन के जरिये जिस समाज-व्यवस्था की कल्पना की गयी थी उसकी साफ तस्वीर न होने की वजह से लाजिमी तौर पर इसकी नीति और कार्यक्रम अश के दृष्टिकोण से ही चलते जा रहे हैं। खादी कार्यकर्त्ता अन्य विशेषज्ञों की तरह कुछ पहलुओं तथा कामों में पूरे माहिर हो जाते हैं और उनके ढर्रे पर ही काम करते हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि खादी आन्दोलन आज भी लोक आन्दोलन की बजाय खादी कार्यकर्त्ताओं का आन्दोलन ही बना हुआ है। बड़े दबाव के अन्तर्गत इसको चलाया जा रहा है और अब भी जनता रूपी जमीन में इसे जड़ पकड़ना बाकी है। इसे जनता के जेहन में उतरना भी बाकी है, क्योंकि वे अब भी ऐसा ही समझते हैं कि यह कार्यक्रम खादी कार्यकर्त्ताओं के जज्बात की तसल्ली के लिए है, न कि जन-साधारण की समस्याओं को हल करने के लिए। इसकी व्याख्या और व्यवस्था ‘अश’ के आधार पर ही की जाती है। इसका पूरा भविष्य समझ सकने में जनता असमर्थ है। उत्पादन की तकनीक के बारे में जो विवाद उठ खड़ा होता है उसमें भी ‘अश’ वाले दृष्टिकोण का बहुत बड़ा हाथ है। पारम्परिक चरखे की जगह अम्बर चरखे अपनाने के कार्य में भी काफी विरोध का मुकाबला करना पड़ा। इस विवाद में कभी-कभी एक पहलू पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि ‘पूर्ण’ नजरअन्दाज हो जाता है और कभी-कभी हालात की कठिनाइयों को आदर्श मान लिया जाता है।

माध्यम

आम तौर से कुछ आर्थिक और सामाजिक मूल्य, जैसे गाँवों की आत्म-निर्भरता और सामाजिक न्याय आदि,

* रेने फुएर कृष्णमूर्ति—दि मैन एण्ड हिज टीचींग।

खादी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। खादी कार्यकर्त्ताओं से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे खादी कार्यक्रम के जरिये इन मूल्यों का भी प्रचार करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष श्री उ न डेबर भी यही चाहते हैं कि खादी कार्यकर्त्ता नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें। गांधीजी के व्यक्तित्व के जोरदार असर की वजह से, जिसका उनके कार्यक्रम के जरिये जनता पर काफी प्रभाव है, हम लोग इन मूल्यों का प्रचार करने में इस व्यक्तिगत तत्व के महत्व पर जोर देने के आदि हो गये हैं, किन्तु मौजूदा परिस्थितियों में, खास कर, इस असर की सीमाओं को महसूस करना मुनासिब होगा।

कार्यक्रम का स्वरूप

कार्यकर्त्ताओं की स्थिति के बारे में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के सदस्य श्री ध्वजा प्रसाद साहू का कहना है कि “पहले के दिनों में किसी सस्था में खादी कार्यकर्त्ताओं के बीच भाई-चारे और बन्धुत्व का वातावरण रहता था, लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ने के साथ ही पुराने रिस्ते टूटते जा रहे हैं और उनकी जगह व्यवस्थापकीय नियंत्रण के विचार आते जा रहे हैं जिसके कारण उस रिस्ते-नाते का बदलना लाजिमी है। खादी आन्दोलन के पीछे विचार यह था कि सूतकार, बुनकर, तथा अन्य कारीगरों का एक परिवार हो। खादी सस्थाओं की व्यवस्था में अब इस खयाल की कोई गुजाइश नहीं रही और अब कारीगरों के साथ मजदूरी पानेवालों का सा सलूक किया जा रहा है।” अब ऐसी स्थिति आ गयी है कि खादी कार्यकर्त्ताओं ने सस्थाओं के साथ अपने सम्बन्धों को नियमित रखने के लिए अपने सब बना लिये हैं। कारीगरों और सस्थाओं के बीच के रिस्ते अब बिल्कुल कार-बारी ढग के हो गये हैं। इन परिस्थितियों में ऐसी उम्मीद करना कि खादी सस्थाएँ या उनके कार्यकर्त्ता नैतिक मूल्यों का प्रचार करें, खामखयाली के अलावा और क्या हो सकता है।

खादी कार्यकर्त्ताओं के व्यक्तिगत असर से ज्यादा भरोसे का जरिया खादी कार्यक्रम का स्वरूप है। कार्यकर्त्ता

भी कार्यक्रम से ही प्रेरणा लेते हैं। इससे भी बढ़ कर बात यह है कि कार्यक्रम के स्वरूप के मुताबिक ही कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। अगर कार्यक्रम प्रेरणा उत्पन्न करनेवाला हुआ तो वह रचनात्मक और मेधावी कार्यकर्ताओं को सिर्फ अपनी ओर खींचने और उन्हें प्रेरणा देने का ही काम नहीं करता, बल्कि जनता पर भी भरपूर असर डालता है। क्या मौजूदा खादी कार्यक्रम में ऐसा कोई आकर्षण है? लोगों की नजर में ऐसा लगता है कि खादी आन्दोलन अपने मौजूदा रूप में स्थिर हो गया है। ऐसा लगता है कि यह मौजूदा सामाजिक ढाँचे की सीमाओं के भीतर काम कर रहा है। सूत-कताई, जो खादी उत्पादन में सबसे ज्यादा तादाद में रोजगारी मुहैया कर रही है, किसानों तथा अन्य लोगों को खाली वक्त के धंधे के रूप में दी जा रही है और वह भी मुस्तकिल नहीं। अभी तक इसे पूरे समय के धंधे के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है कि कृषि की तरफ से हट कर अविकारिक तादाद में लोग इसकी ओर आकर्षित हों। इसलिए खादी, कृषि को सहकारी खेती के रूप में बदलने की दिशा में कोई मदद नहीं पहुँचाती, जिसकी वजह से श्रम-शक्ति फाजिल रह जाती है। राहत पहुँचाने के अलावा आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के मामले में अब तक खादी प्रभावकारी नहीं रही। गाँव और शहर के बीच की असमानता और विभेद को दूर करने में भी इसका शायद ही कुछ असर पड़ सका हो। और, न तो खादी के धंधे ने पढ़े-लिखे बेरोजगारों को राहत पहुँचाने में ही कोई मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान रूप में खादी का हमारी अर्थ-व्यवस्था की बुनियादी और बड़ी समस्याओं से कोई ताल्लुक नहीं है।

बदलता हुआ तरीका

खादी कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर कार्यक्रम के सम्बन्ध में बेचैनी महसूस की है और उसे जाहिर भी किया है। कुछ ने तो खादी कार्यक्रम को सरकार की पंच वर्षीय योजनाओं के एक अंग के रूप में चलाने की

बुद्धिमानी तक पर भी शका प्रकट की है। लेकिन यह देखने की बात है कि सरकार ने कार्यक्रम के स्वरूप या परम्परा को नहीं बदला है। श्री कृष्णदास जाजू ने योजना आयोग के सामने खादी की जो पहली पंच वर्षीय योजना पेश की वह सरकारी सहायता के बल पर खादी कपड़े के उत्पादन के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं थी। विनोबाजी इसे 'अकाली खादी' कहते हैं। फिर खादी कार्यकर्ताओं ने जब अपने दिलों को टटोला तो नया मोड़ का मशहूर फार्मूला सामने आया, जो १९५८ में चालीसगाँव (महाराष्ट्र) सम्मेलन में स्वीकृत किया गया। यद्यपि इस नये फार्मूले ने खादी को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के समग्र विकास की योजना का एक अंग मान लिया है, लेकिन कुछ तो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अधिनियम की पाबंदियों की वजह से और कुछ ऊँची तकनीक—जिन्हें अब माध्यमिक तकनीक कहा जाता है और जो वाकई खादी को अन्यान्य विकासशील अर्थ-व्यवस्था से मिला देगी—को अपनाने में कार्यकर्ताओं की हिचक की वजह से खादी कार्यक्रम अब भी अलग-थलग ही चल रहा है। अब एक बिल्कुल ताजातरीम फार्मूला बिक्री पर दिये जानेवाले रिबेट की जगह पर बुनाई-सहायता लागू करने से ताल्लुक रखता है। इसके जरिये देहाती क्षेत्रों में खादी उत्पादन के विस्तार पर कुछ असर तो पड़ सकता है, लेकिन जहाँ तक सामाजिक ढाँचे को बदलने का ताल्लुक है, यह कार्यक्रम के स्वरूप को शायद ही बदल पायेगा।

मिशन

खादी आन्दोलन को गांधीजी क्या मूल्य देते थे? रान् १९४६ में श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ परामर्श करते हुए गांधीजी ने "मनुष्य के सर्वोच्च बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास" को खादी आन्दोलन का लक्ष्य या मिशन बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि "इसमें सबको बराबर के अधिकार और मौका मिलना चाहिए।" इस आन्दोलन के जरिये वे एक ऐसे वर्गहीन सर्वोदय समाज की स्थापना करना

चाहते थे, जिसमें मनुष्य का सतुलित शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके।

हमारे समाज में वर्ग-विभेद की जड़ क्या है? गीता में वर्णित चारों वर्णों के कर्तव्य-विभेद में उसकी जड़ मिलती है। गीता ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कर्म क्रमशः विद्या-अर्जन, पठन-पाठन और पुरोहिती तथा शासन, युद्ध और राजनीति बाह्य कर्म के रूप में नहीं, बल्कि अन्तर-चारित्रिक रूप में बताये हैं।* वैश्य और शूद्र के कर्म बाह्य कर्म के रूप में बताये गये हैं और इस विभेद का गभीर महत्व है। प्रथम दोनों बाह्य कर्मों को आंतरिक मूल्यों के विकास के लिए क्षेत्र और साधन के रूप में लेते हैं। अन्तिम दोनों प्रायः निष्कासित कर दिये गये हैं और वे अपने कर्मों के चारित्रिक मूल्यों से अधिक बाह्य मूल्यों से चिपके हुए हैं। एक बार कर्मों के विभेद के जरिये व्यक्तित्व के विकास में इस तरह का विभेद आ जाने दिया जाय तो बेहतर से वेहतर राजनीतिक व्यवस्था भी उसे कभी दूर नहीं कर सकती। वास्तविक समानता तो व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर की समानता है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को एक ओर जहाँ यह अवसर मिलता है, वहाँ खाम कर शूद्रों को बाध्य हो कर शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। शारीरिक आवश्यकताओं, जीवन के प्रति मोह तथा समाज द्वारा निर्धारित किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विवशताओं ने उसके पशुवत आलसपूर्ण जीवन पर कठिन कामों का बोझ लाद रखा है। समाज के लिए वह पसीना बहाता है, पर उसकी प्रगति में उसकी कुछ भी देन नहीं है। वह अपनी मेहनत और मेहनताने में ही मनुष्य ह।

* शमो दमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥

शौर्य तेजोवृत्तिर्दक्षिण युद्धे चाग्न्यपलायनम् ।

दानमीश्वर भावश्च क्षात्रकर्म स्वभावजम् ॥

कृषि गोरक्ष्यवाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम्

पारिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥

इस दृष्टिकोण से क्या आज के खादी कारीगर उन शूद्रों की तरह महज बाह्य मूल्यों के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं? खादी आन्दोलन के सामने यही तो आज एक वास्तविक चुनौती है। क्या यह उन्हें अन्तर्मुखी बना सकता है? इसीसे उनका सर्वोच्च विकास होना चाहिए। यही खादी का असली मिशन है - 'स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा।' यथा, जो विवश हो कर हर दम कठिन मेहनत करते रहते हैं और जो सिर्फ बाह्य मूल्यों के लिए ही कार्य करते हैं, इसलिए अविकसित ही रह जाते हैं उन्हें खादी आन्दोलन में अपने कर्मों का रूपान्तर मिलना चाहिए, जो उन्हें अपने आंतरिक मूल्यों के लिए काम करने में समर्थ बनाये।

अलग अलग आत्माएं नहीं

श्री अरविन्द के कथानुसार अलग-अलग आत्माएँ— एक आत्मा ज्ञान की, दूसरी आत्मा शक्ति की, तीसरी आत्मा उत्पादन शक्ति की और चौथी आत्मा सेवा की— नहीं हैं। वे यह भी नहीं मानते कि चौथी आत्मा को क्रमान्तर जीवन से तीसरी और दूसरी आत्माओं से होकर पहली आत्मा में आना पड़ता है। सच तो यह है कि प्रत्येक आत्मा में ज्ञान, शक्ति, उत्पादन-शक्ति और सेवा, ये चारो होते हैं, जिनमें कोई ज्यादा होता है कोई कम। मनुष्य के इन आंतरिक पहलुओं तथा बाह्य कार्यों के बीच गहरे ताल्लुकात हैं। अगर सही तौर पर किया जाय तो शूद्र के काम भी ज्ञान को विकसित करते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं, उत्पादन-शक्ति को सुदृढ़ करते हैं और कौशल की वृद्धि करते हैं। यही सारा सवाल है। कार्यों को किस तरह सही ढंग से किया जाय? इस समस्या का हल निकालना ही खादी आन्दोलन का मिशन है। यह हल भी व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास और वर्गहीन समाज का निर्माण होना चाहिए, जिसमें इस तरह के विकास के लिए सदृश वातावरण उपस्थित हो।

खादी कार्य को किस तरह सगठित किया जाय कि खादी कारीगरों के अन्दर ज्ञान, शक्ति और उत्पादन-शक्ति की वृद्धि हो? क्या खादी अपने मात्र भौतिक

पहलुओ से ऐसा कर रकने में समर्थ हो सकेगी ? जमाने से इस कार्य में लगे हुए खादी कारीगरों की अवस्था से कोई ऐसा मवत नहीं मिलता। भौतिक वस्तुओं में ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी स्थापना या इसका सगठन है—वैज्ञानिक और तकनीकी, सामाजिक और दार्शनिक—जिसके अन्तर्गत कार्य किये जाते हैं। कार्यकर्ता का अतर्मुखी या बहिर्मुखी होना, वह आन्तरिक मूल्यों के लिए काम करता है या बाह्य मूल्यों के लिए, सब कुछ, उसी सगठन पर निर्भर करता है। यह सगठन क्या है जो कार्यकर्ता को आन्तरिक मूल्यों के लिए अतर्मुखी बना देता है ? संक्षेप में यो कहा जा सकता है कि इसमें (१) अस्तित्व के लिए कोई संघर्ष नहीं है, (२) वर्ग-संघर्ष नहीं है, और (३) सादा जीवन तथा उच्च विचार हैं। पहली शर्त विज्ञान और तकनीक के विकास से तात्लुक रखती है, दूसरी सही किस्म के सामाजिक सगठन में और तीसरी जीवन के उपयुक्त दर्शन से।

विज्ञान और तकनीक

“कोई भी अभौतिक सम्भ्यता जीवित नहीं रह सकती। भौतिकता और जीवन यानी प्राण मानव का वास्तविक आधार है। ससार के समस्त बौद्धिक तर्क, समस्त नैतिक आदर्शवादिता और अध्यात्म-वादिता, जिसे मानव-विवेक समझ सकने में समर्थ है, हमारी जीव्यता और भौतिक बुनियाद की वास्तविकता तथा दावे को विलुप्त नहीं कर सकती और न जाति को प्रकृति की अलगनीय विषयता के अन्दर अपने उद्देश्य तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास करने या अपनी बड़ी समस्याओं को मानवीय लक्ष्य, अभिरुचि तथा प्रयासों का बड़ा और आवश्यक अंग बनाने की प्रवृत्ति से रोक सकती है।”

इसी प्रयास में मनुष्य ने विज्ञान तथा तकनीक के विकास के लिए लगातार कोशिश की है, ताकि अस्तित्व के लिए संघर्ष की भीषणता कम हो सके। यही बुनियादी सवाल है। जिस हद तक इसमें सफलता मिलती है, मनुष्य अपने उच्च व्यक्तित्व के विकास की चप्टा के

लिए स्वतंत्र होता है, किन्तु विपरीतावस्था में जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष करते-करते उसकी क्षमता और सामर्थ्य का ह्रास हो जाता है।^१ इसी दृष्टिकोण में उत्पादन और उत्पादकता का विशेष मूल्य है। आशिक दृष्टि से देखने पर हाथ से होनेवाले कार्य का कुछ सीमित महत्व है, लेकिन व्यक्तित्व विकास के पूरे दृष्टिकोण से सबसे अधिक विचारनीय सवाल है विज्ञान और तकनीकी सहायता से अधिक उत्पादन के जरिये जीवन-संघर्ष की भीषणता कम करना। विनोबाजी की राय में मनुष्य को स्वयम् तथा अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिए रोजाना पाच घण्टे से अधिक उत्पादक-कार्य में लगा रहना आवश्यक नहीं होना चाहिए। और, इस भरण-पोषण में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति ही नहीं, बल्कि ऊँचे जीवन की आवश्यकताएँ भी शामिल होनी चाहिए। उत्पादकता का स्तर इतना ऊँचा होना चाहिए कि इस तरह के जीवन-यापन के अतिरिक्त बचत भी हो सके, जिसकी समाज की प्रगति के लिए निहायत जरूरत है। जीवन-यापन की ऐसी परेशानियों से मुक्त होने पर मनुष्य अतर्मुखी हो सकता है।

हाथ के काम पर अधिक जोर प्रायः आदर्श के साथ बेरोजगारी की व्यावहारिक समस्या को उलझा देता है। अगर पहले आदर्श के बारे में सफाई हो जाय, तो समस्त तथ्यों—जैसे समस्त सभ्यताओं के विकास के जरिये विकसशील अर्थ-व्यवस्था और हमारी जनता के उठते हुए व्यक्तित्व के अनुकूल उपभोग और सेवाओं की वृद्धि आदि—को नजर में रखते हुए व्यावहारिक प्रश्न का वैज्ञानिक हल निगाला जा सकता है। इसके लिए लचीलेपन तथा प्रयोग का रास्ता अपनाने की जरूरत है।

खादी कार्यकर्ताओं के अन्दर अनेक वर्षों के विचार-विमर्श और दिल की खोज के बाद अब एक ठोस मतैक्यता स्थापित हो गयी है कि खादी और ग्रामोद्योगों की कुछ प्रक्रियाओं को, खाम कर जो उत्पादन के लिए गत्या-

* ससारण्व लडधनक्षमधियावृत्ति कृता सा नृणाम।
यामन्वेष्टयता प्रयान्ति रूतत सर्वे समाप्ति गुणा॥

वरोध बनी हुई है, यन्त्रीकृत कर दिया जाय। बहुत-से खादी कार्यकर्त्ता भी इस बात को नहीं जानते होंगे कि उसी करघे पर अबर चरखे के सूत की बुनाई का खर्च मिल के सूत की बुनाई से ३५ नये पैसे अधिक पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि हाथ-धुनाई प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने की वजह से अम्बर सूत का गुण खराब होता है। इस प्रकार खादी उद्योग में धुनाई मुख्य गत्यावरोध है जिसका यात्रीकरण होना चाहिए। अगर खादी-उत्पादन का लक्ष्य गाँवों की आत्म-निर्भरता है तो इस गत्यावरोध को दूर कर देना सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है।

किसी धधे को बुद्धिमत्तापूर्ण अपनाना बहुत आवश्यक शर्त है, क्योंकि यही कार्यकर्त्ता को अतर्मुखी और आतर्किक मूल्यों के लिए कार्य करने में समर्थ बनाता है। आज हमारे समस्त उत्पादक धधे—जिनमें खादी, कृषि तथा पशु-पालन भी सम्मिलित हैं—एक तरह से नियमित कार्य हो गये हैं, जिनसे कोई आतर्किक मूल्य नहीं निकलता, वरन् सिर्फ बाह्य मूल्यों के लिए ही उन्हें चलाया जाता है। और, चूँकि अतर् प्रेरणा की गतिशील शक्ति और वैज्ञानिक ज्ञान की भी कमी है, इसलिए बाह्य मूल्यों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। स्वामी विवेकानन्द ने हमारी इस गिरी हुई हालत का कारण हमारी जनता का 'तमस्' बताया है। इजराइल की ग्राम-बस्तियों का सबसे बड़ा सबक यही है कि कार्यकर्त्ताओं का सिर्फ विकसित व्यक्तित्व ही अर्थ-व्यवस्था को विकसित कर सकता है। इजराइल के समस्त किसानों को कृषि धधे में आने से पहले वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया गया—वैसे उनके मामले में यह बात भी है कि उनमें से कोई भी परम्परा से किसान नहीं था इसलिए वैसा करना उनके लिए एक आवश्यकता थी। इजराइल की विकास सेवाओं के अन्तर्गत वहाँ के किसानों को सिर्फ अच्छे किस्म के बीज, खाद, सरजाम तथा कीट-नाशक दवाओं का ही उपयोग नहीं बताया जाता, बल्कि उन्हें कृषि के सभी क्षेत्रों का ज्ञान भी कराया जाता है और जिन्दगी की आम दिलचस्पी के विषय में, जैसे

पुष्टिकर भोजन, सहकारिता तथा दर्शन आदि, शिक्षा भी दी जाती है, जहाँ पुरुषों के साथ महिलाएँ भी बराबर का भाग लेती हैं। इन ग्राम-बस्तियों में पुरुष और नारी दोनों का मानसिक स्तर मैंने काफी ऊँचा पाया। वहाँ का पुरुष वर्ग उत्पादक-कार्यों में सहकारिता या स्वयंसेवी भाव से लगा रहता है और महिलाएँ भी घर के कामों के अतिरिक्त आपसी सहायता, सहकारी दुकानें, शिक्षा, खेल तथा क्रीडा-मैदान आदि समस्त ग्राम-सेवा कार्यों को स्वयं-सेवा के आधार पर सम्भालती हैं। इजराइल बहुत छोटा देश है, इसलिए वहाँ के गाँव बिखरे हुए, अलग-थलग नहीं हैं। पर हमारे लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि उनका जीवन कुछ इस तरह का है कि उनके अन्दर सांस्कृतिक विलगाव भी नहीं है।

खादी आन्दोलन की सफलता, दरअसल, इस बात से आकी जायेगी कि अपने गाँवों के भौगोलिक और सांस्कृतिक विलगाव को दूर करने में हम कहीं तक सफल होते हैं। इस प्रकार तकनीक और नयी तालीम—कोई भी पेशा और कार्य बौद्धिक तथा वैज्ञानिक ढंग से करना—दो ऐसे महान तथ्य हैं जो 'स्त्रियो घैशावस्थता शूद्रा' को अतर्मुखी बनने और आतर्किक मूल्यों के लिए काग करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं।

सामाजिक ढाँचा

वह आदर्श समाज जिसमें मनुष्य अतर्मुखी हो सकता है, एक परिवार का विकसित रूप है। मनुष्य को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह दृष्टिकोण के विस्तार और उच्च प्रेरणा के लिए 'सघ शरण गच्छामि' की भावना से समाज में प्रवेश करे। मनुष्य को चिन्ताओं से मुक्त करने के लिए यह समाज रोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और इस प्रकार वे हालत तैयार करता है कि मनुष्य अतर्मुखी बन जाय। चूँकि प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था मनुष्य को बहिर्मुखी बनाती है, इसलिए यह समाज सहकारी अर्थ-व्यवस्था को अपनाता है जिसमें रवय रोजगारी की पूरी गुंजाइश रहती है। लोगों की मेहनत के फलों को

संग्रहीत करनेवाला व्यापार परिपूर्ण रूप से सहकारी विभाग को सौंपा जा सकता है। सामूहिक उत्पादन की जगह इस तरह का समाज गांधीजी के शब्दों में “जन साधारण द्वारा विकेन्द्रित उत्पादन का संगठन करता है।” अगर केन्द्रित और विकेन्द्रित दोनों व्यवस्थाएँ विज्ञान और तकनीक से पूरा फायदा उठाये तो विकेन्द्रित व्यवस्था में उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि जहाँ केन्द्रित व्यवस्था सिर्फ सर्वाधिक सक्षम इकाई से ही उत्पादन का काम लेती है और अन्य इकाइयों को काम में अलग रखती है, वहाँ विकेन्द्रित व्यवस्था समस्त प्राप्य साधन व स्रोतों का पूर्ण उपयोग करती है और कुल उत्पादन में प्रत्येक* का कुछ न कुछ योग रहता है। इस तरह का समाज, वाकई-कल्याणकारी समाज होगा, जिसमें स्वयं-रोजगारी से पर्याप्त आय होगी और सार्वजनिक सम्पत्ति के सहारे पर्याप्त मात्रा में सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

गाँवों का पुनर्गठन

मौजूदा स्वरूप में, हमारे गाँव उपर्युक्त कल्पना के आधार पर जीवन संचार की प्रेरणा लेने की शायद ही आशा कर सके। वे इतने बिखरे हैं कि आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं की आशा भी नहीं कर सकते। अपने मानसिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए तथा विकास के अवसर विस्तृत करने के लिए उन्हें अपने को अपेक्षाकृत काम की दृष्टि से संप्राण इकाइयों के रूप में पुनर्गठित करना पड़ेगा। राजनीतिक दायरे में उनके इस तरह के संगठन जिला परिषदों के रूप में हैं। आर्थिक दायरे में उन्हें उपयुक्त सहकारी संगठन बनाने पड़ेंगे जो प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त कर स्थानीय साधनों-प्राकृतिक और श्रम-शक्ति-को समस्त सदस्यों के समान लाभ के लिए पूर्ण वैज्ञानिक उपयोग का अवसर देंगे। इस तरह की सहकारी व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग की बड़ी इकाइयाँ

* अमत्र अक्षर नास्ति

नास्ति मूलमनौषधम्

अयोग्यः पुरुष नास्ति

योजकस्तत्र दुर्लभः ॥

उत्पादन की छोटी इकाइयों के पोषक केन्द्र या सेवा केन्द्र की तरह चलेगी, उन्हें दबाने की हरकत नहीं करेगी। इस कार्य के लिए अलग-थलग दूर-दूर बसे हुए गाँवों को सेवा केन्द्रों के जरिये सम्बद्ध किया जायेगा, जिसमें एक केन्द्र कई गाँवों के एक समूह की सेवा करेगा और यही एक रास्ता है जो गाँवों के भौगोलिक विलगाव को दूर करेगा।

विकसित विज्ञान और तकनीक तथा एक अच्छी समाज व्यवस्था मनुष्य को आराम और सामाजिक न्याय दे सकती है, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि वह उसे जीवन के उच्चादर्शों तक भी ले जाय ? इसके लिए उसमें समुचित जीवन-दर्शन का ज्ञान एवं अपने व्यक्तित्व के सतुलित विकास की लालसा का होना आवश्यक है। दर्शन का जीवन पर कितना प्रभावशाली असर पड़ता है, यह तो विभिन्न तौर-तरीकों के समाजों की कार्य प्रणालियों के पर्यवेक्षण से ही पता लगता है।

सादा जीवन

अफ्रीका के आदिम समाजों में वर्गविहीन समाज के बहुत से लक्षण दृष्टव्य हैं। व्यवहारतः वहाँ समस्त उत्पादक कार्य हाथ से ही किये जाते हैं। वहाँ खेती के लिए पशु-शक्तियाँ पुरुष-शक्ति का नहीं बल्कि नारी-शक्ति का उपयोग होता है। यह ऋषी खेती है और अपनी चरमावस्था में। सारी जमीन समाज की है और प्रत्येक परिवार को उसे जोतने और उससे जीविका प्राप्त करने का हक है। अभी हाल तक वहाँ वस्तु या सेवा विनिमय के लिए मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तुओं का ही विनिमय होता था। और, तब प्रत्येक कबीला अपनी निहायत जरूरियाँ तथा सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर था। प्रकृति व बीमारियों से सघर्ष तथा विभिन्न कबीलों के साथ लड़ाइयाँ करते-करते जीवन व्यतीत होता था। यह उस प्राकृत समाज का नमूना

§ धर्मार्थं कामाः सममेव सेव्याः ।

य एकसेवी स नरो जगन्यः ॥

है जिसमें सीधी-सादी जिन्दगी और सीधे-सादे विचार हैं। और फिर, शोषण करनेवाले देशों में हम विकृत समाज का नमूना देखते हैं, जहाँ विज्ञान और तकनीक ने अस्तित्व के लिए सघर्ष तो कम कर दिया है, लेकिन ऊँचे जीवन-यापन के आदर्श की वजह से अस्तित्व के लिए सघर्ष की जगह वर्ग-सघर्ष ने ले ली है। यह उस किस्म का समाज है जहाँ आदर्श की शब्दावली में ऊँची जिन्दगी और साधारण विचार हैं।

इस प्रकार सीधी-सादी जिन्दगी सिर्फ बसर करने के खयाल से या विज्ञान तथा तकनीक ही इतने पर्याप्त या सक्षम नहीं है कि मनुष्य को ऊँची जिन्दगी की खोज में रास्ता बता सके। यह क्षमता तो संस्कृत समाज—सर्वोदय समाज—में ही है, जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देते हुए और भावनाएँ भरते हुए मनुष्य को ऊँचा उठने में समर्थ बनाता है। सर्वोदय समाज प्राकृत समाज की सीमाओं तथा विकृत समाज की कमजोरियों पर काबू पा कर मनुष्य को इस योग्य बनाता है कि वह शारी-

रिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर पूर्ण और सतुलित जीवन व्यतीत कर सके। यह समाज का ऐसा आदर्श है जिसमें सीधी-सादी जिन्दगी और ऊँचे विचार हैं। खादी आन्दोलन का यही मिशन है कि चुने हुए क्षेत्रों में इस तरह के नमूने निर्मित करने के जरिये सर्वोदय समाज की स्थापना की जाय। किन्तु कार्यक्रम के एक अलग-थलग अंग की हैसियत में खादी यह काम पूरा नहीं कर पायेगी, फिर चाहे इसके पीछे कितनी भी श्रेष्ठ भावना क्यों न हो। यह तो तभी सम्भव होगा जब खादी सर्वोदय समाज के पूरे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे समाज के समस्त कार्यों से ऊपर उठ कर एक विशेष रूप अपनाये, एक आदर्श बन जाय। यही महसूस करके गांधीजी ने १९४४ में समग्र कार्यक्रम पेश किया था। सर्वोदय समाज सिर्फ अर्थ-व्यवस्था की ही नहीं, बल्कि मनुष्य की सारी जिन्दगी की समग्रता चाहता है।

नयी दिल्ली १६ अगस्त १९६२

नैतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए पेश किये जानेवाले तत्कालीन तर्कों में कुछ नया नहीं है। जब कोई सरकार विश्वास और आचरण के स्तरीयकरण हेतु असामान्य अथवा अति प्रयास करती प्रतीत होती है तब हम यह पाते हैं कि अधिकतर लूथर, मिण्टन, लॉक, स्पीनोजा, फेनेलॉन, मौण्टेस्क्यू, वालतेयर और मिल की ही उत्कृष्ट बातें दोहरायी गयी हैं। इन लोगों ने कहा है कि विश्वासवाली बातों का निर्णय विवेकपूर्ण आग्रह अथवा दैवी अभिव्यक्ति और प्रेरणा से ही किया जा सकता है, नैतिकता और विचार में समानता लाने का बलवृत्त प्रयत्न तो असफल होगा ही, विचार और निजी नैतिकता के विषय में स्वतंत्रता तो मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार है, और सुख-शान्ति सहन-शक्ति की नीति से ही प्रवाहित होती है।

— फ्रांसिस डब्ल्यू कोकर रिस्पेण्ट पॉलिटिकल थॉट

अम्बर की शक्यता

शकरलाल बैकर

यदि सूतकारों को यह देखने का अवसर मिले कि अम्बर चरखा किम प्रकार दक्षता, कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है तो उन्हें अपनी कुशलता, क्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। परीक्षण और प्रात्यक्षिक केन्द्र इस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहायक हो सकते हैं।

भारत अधिकतर देहातो से बना हुआ है और देहातों की अधिकतर आबादी गरीब, बेकार अथवा अर्ध बेकार है। ग्रामीणों को रोजगारी मिले और उनके जीवन का उचित विकास हो इस दृष्टि में गांधीजी ने खादी की प्रवृत्ति चलायी तथा चरखा सघ व ग्रामोद्योग सघ की स्थापना की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह कार्यक्रम चलाया। स्तराज्य-प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने भी इस कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग मंडल तथा कमीशन की स्थापना की। इस प्रकार के प्रयास के फलस्वरूप आज भारत के करीब एक लाख देहातों में यह प्रवृत्ति फैली हुई है और करीब १५ लाख में अधिक लोग इससे फायदा उठा रहे हैं।

परम्परागत चरखे में सुधार

गांधीजी ने चरखे का काम शुरू किया तब भी देश के अनेक भागों में परम्परागत चरखे चल रहे थे। शुरू-शुरू में इसी चरखे का प्रचार हुआ, फिर भी, इस दिशा में प्रगति करनी हो तो उसमें सशोधन और सुधार करने ही चाहिए, ऐसा गांधीजी का आग्रह रहा। इसलिए परम्परागत चरखे में नये-नये सुधार होते रहे तथा खुद गांधीजी ने इसमें दिलचस्पी ली। फलतः यरवडा चक्र (पेटी चरखे) की शोध हुई और बाद में वे चरखे हजारों की तादाद में चलने लगे। स्कूलों में कताई सिखाने के लिए भी इन पेटी चरखों का उपयोग किया गया।

पेटी चरखा कीमत में सस्ता, वजन में हलका, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए अनुकूल, चलाने में

सरल एवम् हलका, कम जगह घेरनेवाला तथा पर-परागत चरखे की अपेक्षा अधिक उत्पादन देनेवाला बना। इस विशेषता के कारण पेटी चरखे का उपयोग दिन-प्रति-दिन बढ़ता गया।

इस पेटी चरखे के निर्माण के बाद भी गांधीजी को सतोष नहीं हुआ। उनको चाहिए था ८ घंटे में १६,००० गज समान और मजबूत सूत कत सके वैसा चरखा। इसके लिए उन्होंने एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की। कई प्रकार के नमूने आये, लेकिन गांधीजी की शर्त के अनुसार कोई नमूना न बनने के कारण इनाम की घोषणा वापस लेनी पड़ी। फिर भी, चरखे में सशोधन हो, वह पूर्ण रूप से कार्यक्षम बने, ऐसा चिंतन वे करते रहे। साथ-साथ पेटी चरखे पर कतवार की गति बढे, पूनी अच्छी ली जाय सूत अच्छा एवम् अधिक कते, इसके लिए भी वे प्रयत्नशील रहे।

अम्बर चरखा

उसके बाद तमिलनाडु के श्री एकम्बरनाथ ने अबर चरखे का आविष्कार किया। गांधीजी की इनामी चरखे की कल्पना के अनुसार यह चरखा कुछ शर्तें पूरी करता था। खादी काम करनेवालों ने इसे पसंद किया। लेकिन इसमें भी सशोधन की काफी गुंजाइश प्रयोगकारों ने महसूस की और इस दिशा में अधिक प्रयोग करने के लिए सर्व सेवा सघ ने 'अबर प्रयोग समिति' की स्थापना की। इस समिति द्वारा अम्बर चरखे में सशोधन का काम चलता रहा और परिणाम स्वरूप एक

व्यक्ति आठ घंटे में आसानी से ८ से १६ गुण्डी अच्छा और समान सूत कात सके, ऐसे अंबर चरखे का निर्माण किया।

पेटी चरखे पर आठ घंटे में तीन गुडी सूत कतता है और अम्बर चरखे में चार और छ तकुए होने से सूत अधिक कतता है, इसलिए इसके विकास और प्रचार की ओर अधिक ध्यान जाना स्वाभाविक है। पेटी चरखे और अम्बर चरखे की कताई प्रक्रियाये भिन्न है। पेटी चरखे में 'म्यूल पद्धति' के अनुसार काम होता है, जबकि अम्बर पर 'रिंग पद्धति' के अनुसार। 'रिंग पद्धति' में कताई के साथ-साथ तकुओं पर सूत परेतने का काम भी होता है, इसलिए सूत अधिक कतता है, जबकि 'म्यूल पद्धति' में वे दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मिलो में भी अब 'रिंग पद्धति' के अनुसार काम होता है।

धुनाई यंत्र

कताई उद्योग में धुनाई एवम् पूनी बनाने की प्रक्रिया का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले धुनाई का काम पारम्परिक साधनों से होता था। धुनाई अच्छी नहीं होती थी, इसलिए हाथ की मन्दम धुनकी का उपयोग शुरू हुआ। इसके बाद कई प्रकार के प्रयोग हुए तथा धुनाई यंत्र का संशोधन हुआ, और उस पर रूई की धुनाई होने लगी। लेकिन गुण की दृष्टि से उस धुनाई यंत्र पर जो काम होता था, वह सतोषजनक न लगने से यह काम प्रयोग समिति ने हाथ में लिया। अब ऐसा यंत्र तैयार किया जा सका है कि उससे धुनाई करते समय रूई के तंतु अच्छी तरह अलग होते हैं, तंतुओं को बहुत कम हानि पहुँचती है और रूई में से कचरा अच्छी तरह अलग हो जाता है। इस यंत्र के हाथ और पैर दोनों से चलाये जा सके, ऐसे दो नमूने बनाये गये। हस्त-चालित यंत्र पर प्रति घंटा १५ तोला और पैर-चालित यंत्र पर प्रति घंटा ३० तोला रूई की धुनाई अच्छी तरह हो सकती है। अम्बर कताई के लिए पूनी (टेप) भी तैयार हो सके, ऐसी शक्यता भी अब प्रयोगों में दीख रही है।

पेटी चरखे की अपेक्षा अम्बर चरखा कीमत में महँगा

और चलाने में कुछ पेचीदा होने के बावजूद अच्छे गुण-स्तर का अधिक सूत दे सके, ऐसा कार्यक्षम साधन है। आज के प्राविधिक विकास के युग में विकेंद्रित हस्त उद्योग में भी अच्छा उत्पादन दे सके, ऐसे साधन का प्रचार वाछनीय है और इस दृष्टि से ही गांधीजी चरखे की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने का आग्रह रखते थे।

कुछ महत्वपूर्ण पहलू

अम्बर चरखे से सूत अधिक, समान और मजबूत निकलता है, कतवारों को अधिक रोजी मिलती है, बुनकर यह सूत आसानी से अधिक मात्रा में बुन सकते हैं, और उससे अधिक टिकाऊ खादी बन सकती है, इसलिए कताई उद्योग में कार्यक्षम साधन के तौर पर अम्बर का प्रचार हो, यह उचित ही है।

अम्बर चरखा कार्यक्षम होते हुए भी उसके उपयोग एवम् प्रचार के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरणार्थ

१ हरेक कतवार को दिया जानेवाला अम्बर चरखा अच्छा एवम् त्रुटिहीन होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसकी मरम्मत तुरंत हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

२ कतवार को अम्बर की पूरी तालीम देनी चाहिए जैसे, अलग-अलग अकों का सूत कातने का गणित, बट का हिसाब, यंत्र के हरेक पुर्जों की जानकारी तथा यंत्र बिगड़ने न पाये, इस प्रकार चलाने की कुशलता और यदि बिगड़ जाय तो उसे दुरुस्त करने की तालीम आदि। इसके उपरांत किसी कारणवश चरखा कुछ समय बंद रखना पड़े तो वह जग लग कर बिगड़ न जाय, इस प्रकार उसे रखने की जानकारी भी देनी चाहिए।

अलग-अलग अकों का सूत कातने के लिए अलग-अलग प्रकार की रूई काम में ली जाती है। किस अक के लिए कौन सी रूई का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका अभ्यास कतवार को कराना चाहिए। और, वैसी रूई मुहैया करने का प्रबन्ध भी होना चाहिए।

३ टाइपराइटर एव सीने की मशीन चलाना सीख जाने मात्र से आदमी निष्णात नहीं बन सकता, लेकिन उसमें गति के साथ अधिक और अच्छा काम करने के लिए सतत अभ्यास करते रहना जरूरी है। इसी प्रकार अम्बर चरखे की भी तालीम लेने के बाद गति के साथ कताई करते हुए अच्छा और मजबूत सूत कत सके, इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। पेट्टी चरखे पर भी अच्छा और गतिपूर्वक कताने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत रहती है।

गाँवों के लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए हाथ कताई उद्योग अत्यंत महत्व का है। इस प्रवृत्ति के साधनों से काम लेने की समझ और कुशलता के उपरान्त उन साधनों के प्रति लोगों में श्रद्धा जगायी व उत्साह लाया जा सके, ऐसा वायु-मण्डल बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

परीक्षण तथा आदर्श केन्द्र

अम्बर की तालीम पूरी होने के बाद गाँव के लोग अम्बर चरखा अपने घर ले जाकर कताई करते हैं। घर पर किया जानेवाला काम भी अच्छे में अच्छा हो, यह अत्यंत आवश्यक है। यह स्थिति किस प्रकार लायी जा सके, यह एक सवाल है। देहातो में—केन्द्रों में भी—यह काम वास्तव में घर-घर उत्तम प्रकार से चलता हुआ ये लोग प्रत्यक्ष देख सके, तो उस बारे में उनके दिल में विश्वास बढ़ेगा और इस प्रकार यह काम उत्साहपूर्वक करने के लिए वे भी तैयार हो सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग प्रदेशों के खास चुने हुए देहातो में परीक्षण और आदर्श सूत उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जायें और उनके द्वारा अम्बर की वास्तविक क्षमता की प्रतीती क्षेत्रों में हो। इस दृष्टि से घर-घर यह काम शास्त्रीय पद्धति से उत्तम प्रकार का होता रहे। इस प्रकार इस काम को विकसित करने का प्रयत्न किया जाय तो इसके विकास में बहुत ही सहायता मिल सकती है। ऐसे केन्द्रों में आदर्श स्थिति स्थापित हो और बाद में आस-पास के अन्य केन्द्रों के कतवार तथा कार्यकर्ता उन केन्द्रों

का अवलोकन कर सके, वहाँ के काम का अच्छी तरह निरीक्षण कर सके और उसके बारे में महत्व के पहलुओं पर मन को समाधान हो वैसी सही जानकारी एवम् अनुभव ले सके, ऐसी व्यवस्था हो सके तो उससे इस महत्वपूर्ण काम को अच्छा वेग मिल सकता है।

अनाज की अधिक एव अच्छी किस्मों के उत्पादन के लिए कृषि प्रयोग केन्द्र एवम् 'आदर्श फार्म' है। जो किसान अधिक-से-अधिक अच्छी किस्म का अनाज पैदा करता है, उसे इनाम दिया जाता है। पशुपालन के लिए भी वैसी व्यवस्था है। अधिक पैदावार तथा अच्छी नस्ल के पशु गाँवों में लोग देख सकते हैं। ये सुधार कैसे हुए, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और खुद वैसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी तरह यदि अम्बर और खादी में भी उत्तरोत्तर अच्छी प्रगति करनी हो तो उसके साधन और प्रक्रियाओं का प्रात्यक्षिक हो सके, ऐसे नमूने के अबर व खादी केन्द्रों की व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है।

प्रयोग समिति केन्द्र

यह स्वाभाविक है कि अम्बर चरखे की योग्यता और कार्यक्षम उपयोगिता के बारे में अम्बर प्रयोग समिति के सचालक तथा कार्यकर्ता अधिक जानकारी रखते हों। इसलिए यह वाञ्छनीय लगता है कि ऐसे परीक्षण और आदर्श केन्द्र स्थापित करने तथा चलाने का काम प्रयोग समिति द्वारा किया जाय। कताई का काम अधिक परिमाण में जिन प्रदेशों में चलता हो, वहाँ अनुकूल स्थान चुन कर अम्बर की वास्तविक क्षमता के दर्शन हो, इस दृष्टि से परीक्षण केन्द्र स्थापित करने तथा उन्हें चलाने की व्यवस्था प्रयोग समिति करे। ऐसा एक केन्द्र प्रयोग समिति की ओर से गुजरात के श्रीअमीरगढ में चल भी रहा है। वहाँ जो काम हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हरेक राज्य में ऐसे कुछ केन्द्र भी चलाये जायें और अम्बर कताई तथा बुनाई के बारे में शास्त्रीय पद्धति से व्यवस्थित ढंग से प्रयास हो, तो

कार्यकर्ता व कतवारो पर इसका अच्छा प्रभाव पड सकता है और क्षेत्रो मे कार्यक्षमता बढाने मे मदद भी मिल सकती है ।

परीक्षण एव आदर्श केन्द्र खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के मार्गदर्शन मे सस्थाओ द्वारा चलाये जा रहे है । लेकिन सस्थाएँ स्वयम् भी ऐसे केन्द्र अपनी ओर से चलाये, यह वाछनीय है अर्थात् जहाँ ऐसे केन्द्र चल रहे हो उन्हें अधिक विकसित करने तथा जहाँ न हो वहाँ नये केन्द्र शुरू करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए । इस प्रयास की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और ऐसे केन्द्र अच्छी तरह विकसित किये जाय तो इस काम की नीव अधिक सुदृढ हो सकेगी ।

सहज प्रेरणा

देहातो मे ऐसे परीक्षण तथा आदर्श केन्द्र शुरू किये जाय और उनमे वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से उत्तम प्रकार का काम होता रहे, उन केन्द्रो के मातहत अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक सूतकार तैयार होते रहे और अन्य क्षेत्रो के कतवारो को उनका काम दिखाने की व्यवस्था हो, तो उस आदर्श तक पहुँचने के लिए देखनेवाले नये लोग भी प्रेरित होंगे । देहातो की आबादी मे बहुत बडा हिस्सा गरीबो का है । उनके लिए हाथ कताई एक सहायक उद्योग है । उस पर काम करनेवाले को अच्छी कमाई हो तो उस ओर वे सहज ही अधिक ध्यान देगे । उत्पादन बढाने के लिए त्रुटिहीन साधन मुहैया करना और क्षमता बढाने के लिए बौद्धिक और वैज्ञानिक तालीम देना जितना जरूरी है उतना ही उस काम के लिए श्रद्धा और उत्साह का वायुमण्डल बनाना भी । प्रत्यक्ष अच्छा काम हो रहा हो तो उसे देखने से सहज ही वैसा वायुमण्डल पैदा होता है ।

इस सबध मे १९२२ मे गांधीजी के साथ थरवडा जेल मे था उस समय की बातचीत का स्मरण मुझे आता है । गांधीजी उस समय रोजाना चार घण्टे कताई करते थे और घण्टे मे २५० गज सूत कत जाता था । लेकिन वह बहुत कम कतता है, ऐसा गांधीजी को लगता था इसलिए

अधिक गति से कातने का प्रयत्न वे करते थे । श्री मगन-लाल गांधी के पुत्र भाई केशव को सत्याग्रह आश्रम मे एक घण्टे मे ४५० गज से भी अधिक गति से कातते हुए, उन्होंने देखा था । 'इसलिए मैं भी इतना क्यों नहीं कात सकूँ', ऐसा गांधीजी को लगता था । तात्पर्य यह है कि अच्छे और गति से कातनेवालो की टोली इस प्रकार के केन्द्रो मे कातती रहे तो उसे देख कर अन्य कातनेवालो का उत्साह भी बढ सकता है ।

चन्द उदाहरण

इस प्रकार देख कर प्रोत्साहित होनेवालो मे से एक-दो उदाहरण मित्रो से सुने हुए नीचे दे रहा हूँ

साबरमती जेल मे करीब तीन साल पहले अम्बर चरखे दाखिल किये गये । छ माह के प्रयत्न के बाद भी वहाँ के कैदियो की दो गुडी से अधिक गति नहीं आयी । शिक्षक कुशल होने के बावजूद यह स्थिति रहती थी । फिर, कैदियो को प्रयोग समिति के शिक्षको व कार्यकर्ताओ की कताई दिखाने का प्रयोग किया गया । पहले ही दिन प्रथम घण्टे मे ही उनके दिल मे ऐसा विश्वास पैदा हो गया कि ये लोग जिस गति से कातते हैं उस गति से हम भी कात सकते हैं । दूसरे दिन फिर से चार घण्टे तक उनके सामने कताई प्रदर्शन किया गया । फलत सभी कैदियो का विश्वास बढ गया और उनकी गति दो गुण्डी से बढ कर पाँच से आठ गुडी तक पहुँच गयी ।

ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण १९५९-६० के काँग्रेस अधिवेशन के समय का है

प्रयोग समिति के कार्यकर्ता तीन तकुओ का सयुक्त ढोलवाला चरखा नागपुर ले गये थे । उनका दावा था कि वे उस पर चार घण्टे मे आठ गुडी सूत कात सकते हैं । लेकिन भारत मे उत्तम गति से कातनेवाले वर्धा के श्री शामराव मुले ने उस बारे मे शका प्रकट की । इसलिए प्रयोग समिति के कार्यकर्ता श्री रामयादीभाई ने उतनी गति से कात कर दिखाना स्वीकार किया । श्री शामराव आदि घडी लेकर सामने बैठे । चार घण्टे के बाद साढे आठ गुण्डी कती । उसी समय श्री शामराव तथा अन्य

साथियों ने कहा कि अब हम इससे भी अधिक कान सकेगे।

उस प्रकार श्रद्धा और उत्साह पैदा करने तथा उसके लिए वायुमण्डल बनाने में काम का प्रत्यक्ष दर्शन अधिक महत्व रखता है। इस पर से लगता है कि जहाँ खादी प्रवृत्ति अच्छी तरह चल रही हो वैसे सभी प्रदेशों में परीक्षण और आदर्श केन्द्र स्थापित करके विकास करने का भरसक प्रयत्न हो, यह वाछनीय है।

दोनों का महत्व

अम्बर ओग पेटी चरखा दोनों ही महत्वपूर्ण साधन हैं। दोनों का अपना-अपना स्थान है। स्वावलम्बन, अकाल, अतिवृष्टि आदि में राहत कार्य, शारीरिक श्रम कम हो सके ऐसे शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए पेटी चरखा अधिक अनुकूल हो सकता है, जब कि राशकत, गला-कुशल, बुद्धिगामी एवम् अपनी कमाई में

वृद्धि की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों के लिए अम्बर चरखा अधिक उपयोगी हो सकता है।

देहातो में हाथ कटाई का काम पर्याप्त रोजी देनेवाले उद्योग के तौर पर स्थापित करने के लिए अम्बर चरखा कार्यक्षम, आशास्पद और उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन उसे ग्राम विस्तार में प्रचलित करने के काम की ओर विशेष ध्यान देना जरूरी लगता है। ऊपर बताये अनुसार आदर्श केन्द्र तथा आदर्श कटाई करनेवालों के समूहों की रचना हो और उसके द्वारा अम्बर की वास्तविक कार्यक्षमता का प्रत्यक्ष अनुभव खादी क्षेत्र के ग्राम जनो को मिले, ऐसा प्रबन्ध किया जा सके तो अम्बर चरखे को व्यापक बनाने में अधिक सफलता मिल सकती है।

अहमदाबाद २६ जुलाई १९६३

हमें बाहरी भयों से मुक्ति पानी है। भीतर जो शत्रु मौजूद है उनसे तो डरकर ही चलना है। काम-क्रोधादि का भय वास्तविक भय है। इसे जीत लेने से बाहरी भयों का उपद्रव अपने आप मिट जाता है। भय मात्र देह के कारण है। देह विषयक रोग दूर हो जाने से अभय सहज में प्राप्त हो जा सकता है। इस दृष्टि से यह मालूम होता है कि भय मात्र हमारी कल्पना की उपज है। धन से, परिवार से, शरीर से 'अपनापन' हटा दें तो फिर भय कहाँ? 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा'—यह रामबाण वचन है। कुटुंब, धन, देह ज्यों के त्यो रहे, कोई आपत्ति नहीं, इनके बारे में अपनी कल्पना बदल देनी है। यह 'हमारे' नहीं, वह 'मेरे' नहीं है, यह ईश्वर के है, 'मे' उसी का हूँ, मेरी कहलानेवाली इस ससार में कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय किसका हो सकता है? इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जाये, शून्यवत होकर रहे तो सहज में भयमात्र जीत ले, सहज में शान्ति पा जाये, सत्यनारायण के दर्शन प्राप्त कर ले।

— महात्मा गांधी

यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक

जोसेफ दु. सुन्दरम्

गांधीजी एक ऐसे शोषणरहित समाज की स्थापना की कामना करते थे जो कि बिना अधिक सामाजिक अथवा आर्थिक उलट-फेर के आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल से कार्य-भार सम्भालने के बाद, अपने 'नीचे से निर्माण' और नया मोड़ कार्यक्रमों के जरिये गांधीजी द्वारा निदिष्ट इस लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में कमीशन की सफलताओं की समीक्षा करते हुए लेखक, जो कि खादी और ग्रामोद्योग मूल्यांकन समितियों (१९९०) के मंत्री रह चुके हैं, नीति और कार्यक्रम के कई पहलुओं के सम्बन्ध में आलोचनात्मक प्रतीति होते हैं। यद्यपि प्रत्यक्षतः हम डा. सुन्दरम् की समीक्षा से सहमत नहीं हैं, इसे हम इस विश्वास के साथ प्रकाशित कर रहे हैं कि विकास की गति बढ़ाने के लिए मुक्त विचार-विमर्श परमावश्यक पूर्वावश्यकता है। अतः इस लेख में उठाये गये प्रश्नों पर विचार आमंत्रित है।

—सम्पादक

गांधीजी द्वारा खादी ग्रामोद्योगों की की जानेवाली वकालत इस बात पर आधारित थी कि निम्न तीन उद्देश्यों की पूर्ति में इसके द्वारा सहायता पहुँचाने की अत्यावश्यकता वे महसूस करते थे (१) सबसे गरीब वर्ग की मामूली आय में कुछ वृद्धि की जा सके, ऐसे योग्य साधन उन्हें मुहैया करना, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के कार्यक्रम की दिशा में पहला कदम उठाया जा सके, (२) तेजी से बढ़ते हुए शहरों के फल-स्वरूप गाँवों की अपनी सम्पत्ति, उत्पादन तथा मनुष्य शक्ति का जो ह्रास हो रहा है, उसे रोकना तथा (३) परंपरागत भारतीय जीवन के बुनियादी, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की रक्षा करना—खासकर उनके उस अंग की रक्षा करना, जो एक या दूसरे तरीके से, कम या अधिक प्रमाण में, पारस्परिक सहायता, सहकार और परस्पर निर्भरता जैसे सामाजिक गुणों को उनके अन्तःकरण में प्रविष्ट कराने की क्षमता रखता है। गांधीजी के समय में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उनके कारण उनके कार्यक्रम का राष्ट्रीय (राजनीतिक) और सांस्कृतिक (सामाजिक) महत्व भी हो गया था।

विकासोन्मुख तत्व

खादी और ग्रामोद्योगों के पुनर्जीवन और विकास का

गांधीजी का कार्यक्रम, “समय चक्र को पीछे खींचने-वाला” है, ऐसा बताकर कुछ उदार मतवादी आलोचकों द्वारा इसे सामान्यतः या तो ठुकरा दिया जाता था या कुछ आलोचक, जो ‘आधुनिकता’ का दावा करते थे, इसे “स्वप्नदर्शी या सनकी” करार देते थे। तथापि गांधीजी के बहुसंख्य निकट सहयोगी इस कार्यक्रम को अत्यधिक सभाव्यताओं से भरे एक ऐसे क्रांतिकारी साधन के रूप में देखते थे, जो भारतीय जीवन पद्धति के संपूर्ण सत्वाश की रक्षा कर सकता है। लेकिन गांधीजी को अपने कार्यक्रम के प्रति होनेवाली ऐसी प्रशंसाओं या निंदाओं से कोई वास्ता न था, उनका ध्यान मुख्यतः ऐसे सगठित प्रयत्न के कार्यक्रम के विकास की ओर था और उसी ओर लगा रहा, जो जनता को, खासकर ग्रामीणों को, उद्देश्यपूर्ण उत्पादन प्रयत्नों के लिए प्रवृत्त करे जिससे कि ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों को कार्यरूप में लाया जा सके। इसी कारण गांधीजी की दिलचस्पी हाथ करघा बुनकरों के, क्योंकि पहले-पहल बुनकरों ने ही उनका ध्यान अपनी ओर खींचा था, वर्तमान कौशल की सुरक्षा और विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ कर विकेंद्रित कताई उद्योग के विकास की ओर मुड़ी, जिससे कि बुनकरों को सूत की पर्याप्त और निश्चित आपूर्ति अवश्य होती रहे। यही

बात तकनीकी अनुमदान, प्रशिक्षण, कारीगरों की आय बढ़ाने और उत्पादन वृद्धि में उनकी गहरी दिलचस्पी और आग्रह को प्रकट करती है। सुधार के समस्त प्रयत्न, यद्यपि अपने आप में स्वागत योग्य थे, उनकी दृष्टि से पूरे सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के साधन रूप थे। यह उद्देश्य, उनकी राय में, भारतीय जीवन पद्धति के बुनियादी सामाजिक मूल्यों की रक्षा का था। संक्षेप में, उनका सामाजिक कार्यक्रम इस उद्देश्य से प्रेरित था कि शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो सके, जिसके द्वारा बिना किसी सामाजिक या आर्थिक विघटन के आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त हो। इसके फलस्वरूप उनका कार्यक्रम सतत बदलता और बढ़ता रहता एवं उसके मूल तत्व में, सुधार होता रहता, जिसके परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम उतना योग्यतम बनता गया जितना वे बना सकते थे।

तैयारी के दस वर्ष

सन् १९५३ और १९६३ के एक दशक की अवधि में खादी और ग्रामोद्योग का विकास सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए होनेवाले सुयोजित राष्ट्रीय प्रयत्नों का अविभाज्य अंग बन गया है। यह पहली पंच वर्षीय योजना-वधि के अंत में वास्तविक रूप में राष्ट्रीय बन गयी, यद्यपि आरम्भ में उसे राजनीतिक जामा पहनाया जा सकता था। करीब-करीब एक रिक्तता (वैक्यूम) में से ही शुरू करके खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने विधिविहित राज्य मण्डलों को स्थापित करके यह काम आगे बढ़ाया, जो कि अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल द्वारा सन १९५३-५४ में शुरू किया गया था। ये राज्य मंडल खादी ग्रामोद्योग के विकास का राज्यवार कार्यक्रम अमल में लाने की कमीशन की जिम्मेवारी स्वयं उठाने के इच्छुक थे और वैसी क्षमता भी रखते थे। इसके लिए आवश्यक प्रशासनात्मक और सगठनात्मक कार्य पद्धति

का जो क्रमशः विकास, अपनी नीतियों को आर्थिक उन्नति और आर्थिक उत्कर्ष के प्रभावकारी कार्यक्रम के रूप में परिणत करने के लिए कमीशन द्वारा किया गया, वह व्यापक पैमाने के प्रयत्नों के लिए तैयारी करने के अत्यावश्यक समय की समाप्ति का निदर्शक था। अतः प्रस्तुत समय इस बात का विचार करने के लिए उपयुक्त है कि इन उद्योगों के विकास की वर्तमान नीति और दृष्टिकोण योग्य है या नहीं और इससे गांधीजी के ध्येय को कार्यक्रम में सहज ही लाया जा सकता है कि नहीं।

बुनियादी नीति

भूतपूर्व अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल ने 'नीचे से निर्माण' नामक अपने नीति संबंधी वक्तव्य में इस बात का प्रतिपादन किया कि नये उन्नत साधनों और उपकरणों को अंगीकार किया जाय, जिनसे कारीगरों की आय में वृद्धि हो और उत्पादकता भी बढ़े।^१ सगठनात्मक रूप में, उसने शोषणरहित समाज की स्थापना की दिशा में प्रगति करने की दृष्टि से सहकारिता को एक बहुत प्रभावशाली संरचना के रूप में अंगीकार किया।^२ अतः स्वयं-रोजगारी प्राप्त कारीगरों की सहकारी समितियों को उत्तरोत्तर उन्नत किस्म का सामान तैयार करने, जहाँ उत्पादन होता है उन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर उन्हें बेचने, परिवहन खर्च कम करने और अन्य इसी तरह का खर्च घटाने में तथा कुछ अवधि के पश्चात् स्वनिर्भर इकाइयों की स्थिति उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए सहायता देने की बात की गयी।

समग्र विकास, जो कि 'नया मोड' के नाम से जाना जाता है और जिसे तीसरी पंच वर्षीय योजना के आधार के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, जहाँ तक खादी-ग्रामोद्योगों के विकास का संबंध है, वही कार्यक्रम है।^३ तथापि, कम से कम प्रारम्भिक काल में, सगठनात्मक स्वरूप के लिए योग्य नेताओं द्वारा बनायी गयी स्थानीय

१ 'बिल्डिंग फ्रॉम बिलो' अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल, १९५६ अध्याय ५ और ८।

२ वही।

३ 'थर्ड फाइव ईयर प्लान फॉर खादी', खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, १९६१।

समितियों पर जोर दिया गया, यद्यपि सगठन के अंतिम स्वरूप के तौर पर बहुधर्मी सहकारी समितियाँ ही रहेंगी। उसका जोर, पूर्व के 'नीचे से निर्माण' के समान ही, उन्नत साधनों और उपकरणों का अंगीकार करने, उच्च उत्पादकता, अल्प लागत और कम मूल्य पर तथा अधिकतम आय पर ही रहा।^४

नीति और व्यवहार

स्थूल नीति सबकी वक्तव्यों के रूप में तो 'नीचे से निर्माण' का और न 'नया मोड़' का ही उस बुनियादी सामाजिक उद्देश्यों से संघर्ष आता है, जिसके लिए गांधीजी चाहते थे कि इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम को अमल में लाया जाय। पर कथनी और करनी में सतत बढ़ती हुई खाई केवल उस समय दिखाई देती है, जब प्रत्यक्ष कार्यक्रम, उसकी संरचना और उसकी गत्यात्मकता का अध्ययन उन उद्देश्यों के मदर्भ में किया जाता है। ये कार्यक्रम अपने मूल स्वरूप में आपत्तिजनक नहीं लग सकते, क्योंकि अन्ततः सहायित प्रयत्नों के लिए किये जानेवाले अनेकविध उपायों से अधिक उनका स्थान न था, परन्तु कमीशन द्वारा अपनाये हुए स्थायी महत्व के उपाय या कमीशन द्वारा सहायित और प्रोत्साहित प्रयत्न दूसरी ही श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। कमीशन ने अपने कार्यक्षेत्र में आनेवाले प्रत्येक ग्रामोद्योग का और खादी का सन् १९५३ से १९६३ तक की दस साल की अवधि में जो विकास किया, उसे यदि बड़ी-बड़ी आर्थिक सहायताओं और उनके उपयोग, उत्पादन और बिक्री तथा कमीशन द्वारा मान्य और पजीकृत नयी संस्थाओं की संख्या की दृष्टि से सन् १९५३ या अन्य किसी कथित वर्ष की स्थितियों से तुलना करे तो वह वास्तविक खर्च के ठीक अनुरूप और प्रभावशाली लगेगा भले ही प्रगति सबकी अधिकारिक वित्तीय मूल्यांकन इस दावे के बारे में सवाल उठा सकता है, प्रगति

का वास्तविक या सच्चा माप वस्तुतः उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की दर नहीं है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का वह स्वरूप ही है जो प्रत्यक्ष रूप से लाया गया हो या उसके लिए तैयारी की गयी हो। इसी दृष्टि से नीचे कुछ मतव्य एवं सुझाव पेश किये जा रहे हैं।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में खादी-ग्रामोद्योगों का जो स्थान है, उसका औचित्य अतिरिक्त पूँजीगत लागत बहुत कम मात्रा में लगाकर या उसके बिना ही व्यापक पैमाने पर जरूरतमंदों को रोजगारी देने की उसकी क्षमता में है। अम्बर चरखा कार्यक्रम शुरू किये जाने के कारण विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता स्वभावतः पैदा हुई। प्रयत्नस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ाने का आश्वासन, सूत की सुधरी हुई किस्म, लागत मूल्य में कमी और इस कारण रिबेट और सब्सिडी की दरों में भी होनेवाली कमी से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचित्य सिद्ध किया जाता है।^५ दावा किया गया कि अम्बर चरखा कार्यक्रम इस योग्य है कि स्वस्थ शरीरवाले लोगों को पूरे समय की रोजगारी मुहैया करके वह अपनी ओर आकृष्ट करेगा, जिससे भूमि पर का दबाव कम होगा।^६

निरपेक्ष मूल्यांकन

परन्तु खादी के विकास और उसमें अम्बर चरखा कार्यक्रम के योगदान की सूक्ष्म छानबीन से इन दावों को कोई समर्थन नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और कमजोर वर्गों ने साधारणतया सम्पूर्ण उद्योग को नजरअंदाज ही किया है, क्योंकि उन्हें इसमें स्थायी आर्थिक महत्व का कोई आश्वासन नहीं मिला।^७ अम्बर या परंपरागत चरखे द्वारा जिन्हें रोजगारी दी गयी, उन्होंने केवल आशिक समय के लिए ही उस पर काम किया। पूरे समय काम करनेवाले लोग, संख्या की दृष्टि से अथवा

४ थर्ड फाइव ईयर प्लान फॉर खादी, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, १९६१।

५ दि अबर चरखा प्रोग्राम, इट्स इकनॉमिक्स, अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल, १९५६।

६ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान, अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल, १९५६।

७ रिपोर्ट ऑफ दि खादी इवेल्यूएशन कमिटी, अध्याय ८।

अन्य किसी भी दृष्टि में महत्वहीन ही रहे।^८ तथापि विशेष महत्व की बात यह है कि, ऊपर बतायी हुई महत्वहीन सख्या को छोड़ कर, अम्बर या परंपरागत चरखों के सूतकारों की आय बहुत ही कम रही, इसलिए आर्थिक प्रगति के बुनियादी उद्देश्यों के प्रति, जो कि माली राहत से भिन्न वस्तु है, उनका योगदान नगण्य रहा।^९ पुरुष सूतकारों को आकर्षित करने और उन्हें इस काम में टिकाये रखने के कार्य में, वर्तमान सामाजिक और अन्य बाधक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, खादी को करीब-करीब पूरी असफलता ही प्राप्त हुई और इस असफलता का दोषारोपण आर्थिक महत्व की रोजगारी के स्रोत के रूप में इस कार्यक्रम की जो बुनियादी अपूर्णता है, उसी पर होना चाहिए।^{१०}

उसी तरह, हाथ करघा बुनकरों को पर्याप्त और नियमित रूप से सूत की पूर्ति की जा सके, ऐसा आश्वासन देने की दृष्टि से भी खादी-कार्यक्रम असफल रहा है। जो कुछ भी कारण हो, हाथ-करघा सूत करघा-बुनकरों की उत्पादकता और उनकी आय की दृष्टि में अवरोध ही बना रहा है, और कपड़े की किस्म में काफी हद तक गिरावट होने के बावजूद बुनाई की लागत भी सामान्य-तौर पर ऊँची ही रही है। मिल सूत बुननेवाले बुनकर हाथ-सूत का उपयोग करने के लिए राजी हो सके, इसके लिए उन्हें काफी प्रलोभन देने होंगे और साथ ही उन्हें हाथ-सूत के उपयोग का प्रारम्भिक प्रशिक्षण भी देना होगा।^{११} खादी सस्थाओं के बुनकर खुले रूप में इस नियम की, कि मिल सूत से वे कपड़ा न बनावे, जो अवहेलना कर रहे हैं,^{१२} वह मिल सूत के योग्य विकल्प के रूप में हाथ-कते सूत की तकनीकी और आर्थिक असफलता को ही प्रकट करती है।

खादी-कार्यक्रम में, विशेषतः अम्बर चरखा कार्यक्रम

में, लगनेवाले पूँजीगत व्यय की तुलना में कोई प्रशसनीय प्रगति हुई है, ऐसा किसी भी दृष्टि से नहीं दिखायी देता। वितरित कुल अम्बर चरखों में से अनुपयोगित पड़े हुए अम्बर चरखों के प्रातिशत्य, बेकार और दोषपूर्ण चरखों के नवीनीकरण और सुधार पर होनेवाले खर्च, उस पर कते हुए सूत से बनाये गये कपड़ों की गिरी हुई किस्म और सबसे अधिक तो इनके कारण खादी की फुटकर बिक्री के बाजार की जो गम्भीर स्थिति हो गयी है तथा सस्थाओं का स्टॉक बढ़ गया है, इनके आधार पर गणना करने से इस पूँजीगत व्यय को नगण्य नहीं कहा जा सकता।

प्रशिक्षितों की सम्भावना

कुल मिलाकर हमारे खादी कार्यक्रम का, ओर अम्बर कार्यक्रम का, जैसा कि विशेष रूप से उसका कार्यान्वयन हुआ है, सबसे बड़ा दोष यह है कि लोगों को प्रशिक्षण देने में समय, शक्ति और धन का बड़ा अपव्यय हो रहा है,^{१३} क्योंकि इन प्रशिक्षितों की न तो आज, न आगे ही खादी या अन्य किसी उद्योग में कोई मांग है। यदि कपड़ों की दिन प्रति दिन उन्नत हो रही किस्मों के बढ़ते उत्पादन को सतत निम्न दरों पर बेचना सम्भव होता, तो अम्बर चरखे के सूतकारों के लिए काफी अधिक, यद्यपि सीमित क्षेत्र में, मांग हो सकती थी। तेजी से गिरती हुई कपड़ों की किस्म, अशत, ऊँची कीमतों के और अशत लोगों की सतत गिरते जानेवाली आय के कारण कपड़े की माँग जो कम होती जा रही है, वह इस बात की ओर इंगित करता है कि अम्बर के सूतकारों के लिए कोई वास्तविक माँग नहीं है और विभिन्न श्रेणी के लोगों को दिये जानेवाले प्रशिक्षण पर होनेवाले खर्च की तुलना में आर्थिक या सामाजिक रूप से कोई स्थायी महत्व की या प्रशसनीय प्राप्ति नहीं हुई है, न होने की सम्भावना है। देर या अबेर इन “प्रशिक्षित” लोगों को, जहाँ भी सभव हो, दूसरे कामों की शरण में जाना ही होगा।

८. वही।

९. वही।

१०. वही।

११. वही, सहायता के विवरण के लिए परिचय पुस्तिका सहा-

यता का विवरण भी देखिए।

१२. खादी इवेल्यूएशन कमिटी रिपोर्ट, अध्याय ८

१३. प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामों के विवरण के लिए देखिए खादी इवेल्यूएशन कमिटी रिपोर्ट, अध्याय ८ और १०।

अनियमित और निर्भरीय होने के बावजूद पर्यायी काम, जैसे सड़के बनाना, मेडे बनाना आदि, सूतकारों को अपनी ओर खींचते रहते हैं, क्योंकि सूत कताई से वस्तुतः इतनी आय हो ही नहीं सकती। दूसरे शब्दों में, अम्बर या परंपरागत चरखों पर सूत कताई ऐसी कला या कौशल नहीं है, जो “बिक्री योग्य” हो, जैसे कि बढईगीरी, लुहारी, राजगीरी आदि है। सूतकारों की ‘कला’, या ‘कौशल’ की मांग कुछ सस्थाओं तक ही सीमित है, जिनके कार्य उन अनेक विध-विचारों पर आधारित रहते हैं, जो कारीगरों की जरूरतों से सर्वथा असंबंधित होते हैं।

विकेन्द्रीकरण और खादी

परन्तु उपर्युक्त सूक्ष्म मूल्यांकन से विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता के बारे में कोई शका नहीं उठती। औद्योगीकरण के साथ-साथ आनेवाले नागरीकरण का सामाजिक मूल्यांकन, सामाजिक जीवन के विकेन्द्रीकरण का ही महत्व निर्देश करता है, जो कि मानव और उसके नैतिक मूल्यों को बचाने की दृष्टि से एकमात्र सभ्य उपाय है। परन्तु आर्थिक संगठन और प्रवृत्तियों का विकेन्द्रीकरण भी उत्पादन के आधुनिक और अत्यधिक उन्नत तकनीकों को अपनाते से विरत नहीं करता,^{१४} जैसा कि अमेरिका, इंग्लैंड और स्वीट्जरलैंड का अनुभव बताता है। आवश्यक कौशल की प्राप्ति, जिसमें यद्यपि समय लगता है, कारीगर को काम के चुनाव के कई मौकों उपलब्ध करा देती है, और इसलिए कई पर्यायी कामों या व्यवसायों का उपयोग लेते रहने का अवसर उसे मिलता रहता है। दूसरे शब्दों में, उसे वह बाजार के उपयोग के योग्य कौशल प्रदान करती है, फलतः उसे आत्मनिर्भर, उपयोगी और उत्पादक कारीगर बना देती है, जबकि सूतकार सभवतः कभी ऐसा नहीं बन सकता। बढईगीरी या ऐसा ही कोई काम सीखने में निस्संदेह सूत

कताई की तुलना में अधिक समय लगता है, लेकिन औसत कौशलवाला मेहनती बढई भी समान समय काम कर उस बहुत कुशल सूतकार की बनिस्बत कई गुना अधिक कमा लेता है। अतः यहाँ प्रश्न कौशल की पसंदगी का है, न कि बृहत् प्रयास का, और यही महत्वपूर्ण बन जाता है।^{१५}

वस्तुनिष्ठ या निरपेक्ष दृष्टि से देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि व्यापक और दुर्बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो अम्बर चरखे के कारण आवश्यक हो गया है, के अन्तर्गत प्रशिक्षित उन बहुसंख्य लोगों को ऐसा कौशल सिखाया गया है, जो कि ‘खुले बाजार’ में बिक्री योग्य हो। निस्संदेह, खादी के लिए हाथ-कताई करनेवालों की जरूरत है, लेकिन उसमें ऐसी क्षमता नहीं है कि मान्य दर से मजदूरी चुका सके। यह राहत पहुँचाने में बड़ा सफल हुआ है। परन्तु वह भी यदि निरपेक्ष रूप से देखे तो, सीमान्त स्तर पर ही हुआ है। व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने पर पूरी तौर से अस्थायी या क्षणिक महत्ववाला महज राहत का कार्यक्रम क्या इतनी अधिक आर्थिक सहायता पा सकता है या पाने के लिए मांग कर सकता है जितना कि अम्बर चरखा कार्यक्रम के लिए आवश्यक है? प्रत्यक्षतः निरपेक्ष मूल्यों से रहित कौशल का प्रशिक्षण मुश्किल से यह दावा कर सकता है कि वह राष्ट्रीय है अथवा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ एकरूप हो सकने योग्य स्थायी महत्व का है।

तकनीकों अनुसंधान

अच्छे साधनों और उपकरणों का विकास करने की दृष्टि से अलग-अलग सस्थाओं को कमीशन द्वारा अनुदानों के रूप में पर्याप्त व्यय करने की स्वीकृति दी गयी है। उसने अपनी एक अनुसंधानशाला भी स्थापित की है और सस्थाओं तथा एजेंसियों द्वारा सिफारिश किये गये

१४ भारत की कौशलहीन जनता की परिस्थितियों के साथ उसका संबंध कैसे बैठता है, इसके विवरण के लिए तुलना कीजिए, बिल्डिंग फ्राम बिलो, भाग-२।

१५ समाज के पिछड़े हुए वर्गों से कारीगर कौन-से बिक्री

योग्य कौशल प्राप्त कर सकता है इसमें विस्तृत विवरण के लिए देखिए, ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी का इकनॉमिक रिव्यू भाग १५, स ३१७, जुलाई १९६३, पृष्ठ २६ और आगे।

कारीगरो की भी सहायता इसके लिए की है। पर यहाँ भी, प्राप्त निष्कर्षों के सबध में वस्तुनिष्ठ दृष्टि में विचार करने की आवश्यकता है।

सन् १९५०-५९ के दशक के प्रारम्भ में, अम्बर चरखे का प्रथम नमूना बनने के बाद से, अखिल भारत सर्व सेवा सध, उससे सबधित सस्थाओं तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा अनुसंधान पर जो खर्च हुआ है, वह काफी है, परन्तु किस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में यह अनुसंधान कार्य हो रहा है? किसी नये 'तकनीक' को खोजने का प्रश्न तो कहीं था ही नहीं। विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए पहले से जाने हुए और पूर्णतः प्राप्त तकनीकों को अपनाने का ही प्रश्न था। परन्तु जो कुछ हुआ, वह यही कि कीमती वस्तु, शक्ति और पैसों का व्यय छोटे-मोटे सुधार करने जैसे प्रयासों पर हुआ है और केन्द्रित उद्योगों के रूप में वर्णित उद्योगों पर जो निर्भरता है, उसे दूर करने या काफी हद तक कम करने के साधन और रास्ते ढूँढने पर ही खर्च हुआ है। इनमें से कुछ केन्द्रों में जो समाधान खोजे गये, उनमें से कुछ साधन कार्य करने की दृष्टि से "स्वीकृत उद्देश्यों" के सदर्थ में "सक्षम" माने जा सकते हैं, पर पूर्णतः ग्रामों में ही बन सके, ऐसे साधन ढूँढने में ही शक्ति लगाने के बारे में अवश्य प्रश्न किया जा सकता है। यह बात उस समग्र अर्थ-व्यवस्था की संपूर्ण धारणा के ही विपरीत चली जाती है जिसके अनुसार हरेक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर रहता है और प्रत्येक दूसरे की सहायता करता है। यह उन सभी बड़े उद्योगों की परिलक्षित निन्दा है, जो कि स्वतंत्र भारत में उतने ही "स्वदेशी" हैं, जितनी कि "खादी" दावा करती है। "रूढ़िवादी" (या पूर्व कालीन अपि-रिवर्तनकारी?) रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के प्रभुत्व के कारण तकनीकी अनुसंधान उपाहासात्मक बन कर रह गया है। करीब एक दशक बाद भी, कमीशन के क्षेत्र में आनेवाले किसी भी उद्योग के किसी प्रशोधन कार्य के उपकरण में उन्नत तकनीक दाखिल करके उसे विकसित किया गया हो, ऐसा नहीं दिखायी देता। तथाकथित 'तकनीकी अनुसंधान' ऐसा कोई उपकरण ढूँढ निकालने

में असफल रहा, जो तकनीकी और कार्यक्षमता, उत्पादकता, उत्पादन की प्रति इकाई लागत और फलतः मूल्य की दृष्टि से सतोपकारी हो। प्रयोगशालाओं में जो उपकरण खोजे गये, यद्यपि वे आज उपयोग में आनेवाले साधनों से निश्चित ही श्रेष्ठ हैं, पर वे विशेष रूप से उच्च उत्पादकतावाले नहीं हैं अथवा मान्य तकनीकों के सफल अंगीकार का भी प्रतिनिधित्व वे नहीं करते या मानकीकरण और बड़े पैमाने पर निर्मित करने योग्य भी नहीं हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि विशेषता युक्त और व्यवितगत ध्यान, जो प्रयोगशाला में देना संभव है, क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कारीगर वह आवश्यक कौशल अपने में न रखता है, न विशेष वक्त खर्च किये बिना उसे प्राप्त ही कर सकता है, जो कि ऊपर बताये अनुसार, किसी तरह के भौतिक लाभ की संभावना नहीं बताता।

असली परिवर्तन का विरोधी

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उस पर से यह खयाल स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि किसी प्रकार का अनुसंधान कार्य हुआ है और वह चल भी रहा है, फिर भी प्रभावशाली रूप से अपनाने और उच्च उत्पादकता में सहायता पहुँचानेवाले उन उन्नत साधनों एवम् उपकरणों की खोज करने, जो पूरे समय काम करने के इच्छुक और योग्य ऐसे स्वस्थ शरीरवाले लोगों को उद्योगों में टिकाये रखने और आकर्षित करने लायक हों, की दिशा में सच्ची एकाग्रता से प्रयास नहीं किया गया है। तकनीकी अनुसंधान कार्य को रूढ़िवादिता ने सदा रोका है और यही स्थिति आज भी चली आ रही है। यह रूढ़िवादिता ही असली परिवर्तन का विरोध करती है। इस सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण और प्रवृत्ति ने ही कमीशन को अनेक समितियाँ जैसे ग्रामीण और लघु उद्योग (द्वितीय पंच वर्षीय योजना) समिति, खादी और ग्रामोद्योगों के लिए मूल्यांकन समितियाँ तथा शक्ति समिति, के उपयुक्त सुझावों पर अमल करने से रोका है। इसका फल यह हुआ कि बुनियादी नीति को प्रभावित करनेवाली सिफा-

रिशो और इस कार्यक्रम को वास्तविक रूप से सामाजिक तथा आर्थिक महत्व प्रदान करनेवाले सुझावों की स्वीकृति केवल जबानी जमा खर्च तक ही सीमित रह गयी। व्यवहार में ये सारे कार्यक्रम वैसे ही बने रहे और उसी प्रकार प्रभावहीन रहे, जैसे कि इन समितियों की जाँच और रिपोर्ट के पूर्व थे।

उद्देश्यपूर्ण उपयोगितावाद

रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सिद्धान्तवादी दृष्टि ही वास्तव में प्रभावशाली कार्यक्रम की प्रगति में बाधा पहुँचाने के लिए उत्तरदायी रही है। हर चीज को समझते हुए रचनात्मक आलोचना करने पर भी ऐसा जोशीला और अक्सर असंगत बचाव किया जाता रहा है कि जिससे सुझावों का सार भी दुर्लक्ष हो जाता है। इन परिस्थितियों में विकास कार्यक्रम रोजगारी की स्थिति पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने में असफल सिद्ध हुए तथा उनके बचाव की सभी दलीलें और दावे, सब कुछ कहे और किये जाने के बाद, खाली और प्रभावहीन रहे।

बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अर्द्ध-रोजगारी की सच्चाई के बारे में अब कोई प्रश्न नहीं रहा है, परन्तु जो सदेह किया गया और किया जाता है, वह बेरोजगारी की भीषण समस्या को हलका बनाने के साधन के रूप में खादी-ग्रामोद्योगों की प्रभावशीलता के बारे में है, जिसका कारण यह है कि एक पूरे दशक की अवधि में भी कहीं भी बेरोजगारी और अर्द्ध-रोजगारी की समस्या, किसी भी प्रशंसा योग्य पैमाने पर, हल करने में ये पूर्णतः असफल रहे हैं। इन उद्योगों से हट कर श्रमिकों का भारी सख्या में किसी दूसरी रोजगारी में लग जाना इसी बात को प्रकट करता है कि अपर्याप्त आमदनी होने के कारण वे इन उद्योगों में काम करते रहना नहीं चाहते।

वे बुनियादी सिद्धान्त, जिनसे अनुप्राणित होकर गांधीजी ने खादी की वकालत की, आज भी उतने ही सत्य हैं, जितने कि उनके जीवन-काल में थे। खादी एक विशेष तकनीक के द्वारा उत्पादित उपभोक्ता सामग्री होने के

अतिरिक्त, सामाजिक बुराइयों के प्रति सवेदनशीलता का भी प्रतिनिधित्व करती है। ससार की परिवर्तित स्थितियों में खादी का अपने खुद के मूल्यों और अधिमानों के पैमाने पर जो बुनियादी सिद्धान्त है, वह प्रसंगोचित है, क्योंकि उसका स्थायी मूल्य है।^{१६} मानवीय कार्यक्रमों के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में खादी एक विकेंद्रित, आर्थिक एवं सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करेगी, विशेषतया इसका स्वरूप ऐसा होगा कि वह जन-सख्या के जीवन-स्तर को ऊँचा उठायेगी और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के अवसरों की असमानताओं को कम करेगी।

बीते जमाने का दृष्टिकोण

बार-बार दुहराया जानेवाला “आत्मनिर्भरता” का आदर्श आज की परिस्थितियों में सर्वथा अप्रासंगिक और बीते जमाने का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में जन्मता है और सिर्फ अपने ही समाज में वह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। धर्म, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के साथ ही आर्थिक क्षमता सहकारी प्रयासों तथा सामान्य आदर्शों के प्रयत्नों को अपरिहार्य कर देती है। आत्मनिर्भरता के विचार द्वारा तिरस्कृत श्रम विभाजन सभी कार्यक्रमों को आधार देता है। राजनीतिक, आर्थिक तथा जनकिकीय प्रवाह आज विश्वव्यापी चिन्तन की आवश्यकता पर जोर देता है और आणविक विकासों ने राष्ट्रीय सीमाओं तक को भूल जाने की आवश्यकता पैदा कर दी है, जैसे कि अब वे सचमुच अर्थहीन हो गयी हैं। इस सदर्थ में, आत्मनिर्भरता के लिए पुकार मचांना या भारी उद्योगों पर निर्भर रहने से बचना अवश्यम्भावी यथार्थताओं का मुकाबला करने से पीछे भागना ही है। यथार्थता का यही अभाव बौद्धिक जडता की बुनियाद में है, जो सकल्पपूर्वक आगे बढ़ने से रोकती रहती है।

१६. खादी विचार की पूर्ण जानकारी के लिए तुलना कीजिए रिपोर्ट ऑफ खादी इवेल्यूएशन कमिटी, अध्याय २।

इसी प्रकार सगठन और रोजगारी के स्वरूप के मब्ध मे भी कई बाधाएँ हैं। आमतौर पर यह माना जाता है— जो मानो स्वयं सिद्ध ही हो—कि कारखाना सगठन या अन्य किसी रूप में रोजगारी में बुरे हैं और सहकारी सगठन स्वतः उच्चतर हैं। वैयक्तिक अभिक्रम और उद्यम में एक व्यक्ति के दूसरे के ऊपर हावी होने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, और सहकारी संस्था में रोजगारी, यदि उसका प्रबन्ध निहित स्वार्थवाले व्यक्तियों के हाथ में हो तो, फ़ैक्टरी की रोजगारी से भी बदतर हो सकती है। सभी खादी संस्थाएँ समान रूप से दयालु नहीं हैं, और न सब-के-सब फ़ैक्टरी मालिक या मैनेजर क्रूर शोषक ही होते हैं। यथार्थवाद इन बीते समय के पक्षपातों को दूर फेंकने की आवश्यकता का संकेत दे रहा है। प्रजातंत्र में मानवीय कार्यकलापों का अंतिम नियामक जागृत और जिम्मेवार जनमत ही होता है। विकास कार्य को सभी कार्यकलापों की प्रभावशाली तथा सामाजिक रूप में सार्थक समग्रता की समस्या के रूप में देखनेवाली नयी सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक जरूरतों और समस्याओं के प्रति भावनात्मकता की शिक्षा देनी होगी। स्वमताग्रह तो केवल प्रगति रोकने का ही काम करता है और उद्देश्ययुक्त प्रयत्नों को प्रोत्साहित नहीं करता।

कल्याण का उत्तरदायित्व

आधुनिक, औद्योगीकृत और तीव्र गति से विकसित होती हुई अर्थ-व्यवस्था के सदर्थ में यह मान्य है कि सामाजिक कल्याण का उत्तरदायित्व सरकार, मालिक और कर्मचारी इन तीनों का है। हाल के श्रमिक, फ़ैक्टरी और औद्योगिक विधि-विधान इस बात की दृढ़ स्वीकृति पर आधारित है कि सामाजिक कल्याण में त्रिदलीय आयोजन, सहयोग और प्रशासन निहित है और सरकार की भूमिका निश्चित ही एक पक्ष की तरह है। अतएव हमारे लिए यह जरूरी है कि इस सदर्थ में हम सगठन के सभी स्वरूपों और नमूनों को विकास की सामाजिक-आर्थिक परियोजना में समान और समझदार भागीदार के रूप में ग्रहण करें। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, जो कि

व्यक्तिगत उद्योगकर्त्ताओं के व्यापार की सभाव्य लाभकारी भूमिका को मान्यता देता है, विकास को शीघ्र सरल बना सकता है, क्योंकि वह समुदाय के अधिकांश उद्यमी और उन्नति के लिए तत्पर लोगों के सक्रिय सहयोग को प्राप्त कर सकेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग, श्रम और सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करनेवाले मौजूदा कानून सर्व-साधारण रूप से व्यापक हैं, और यदि उन्हें प्रभावकारी रूप से लागू किया गया, तो वे बिना किसी बड़े परिवर्तन के, समाज के सभी वर्गों के अधिकार की रक्षा कर सकेंगे, एवं उनके विशेषाधिकारों को भी प्राप्त कर सकेंगे। सबके द्वारा स्वीकृत आदर्शों की प्राप्ति के लिए सामान्य समस्याओं के हल के प्रति पारस्परिक दायित्वों की सामाजिक चेतना सभी विकेंद्रित सामाजिक विकास की अनिवार्य शर्त है, और यह वही उद्देश्य है, जिसका उत्साह के साथ निरंतर पालन और प्राप्ति के प्रयत्न होने चाहिए।

यथार्थतायुक्त पुनर्गठन

ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक विकास सबधी सही और समग्रतायुक्त दृष्टिकोण विकसित करने में जो बाधाएँ वर्तमान हैं, वे उपर्युक्त विचारों को स्वीकार करने से दूर हो सकती हैं। विचार और कार्य स्वयमेव आर्थिक बुराईयों को दूर करने की नीति और उपायों को प्रतिबिंबित करेंगे, क्योंकि वे अपनी शक्ति सीधे समुदाय से ही प्राप्त करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, अखिल भारत हाथ करघा मण्डल व लघु स्तरीय उद्योग मण्डल के कार्यों की भूमिका और कार्यक्षेत्र का जो सर्वथा असमर्थनीय विभाजन हुआ है, वह ग्रामीण विकास मंडलों की स्थापना कर दूर किया जा सकता है, जो कि सभी आर्थिक हितों की महभागिता के लिए योग्य सघटनात्मक ढांचा प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी कार्यक्रम पर जन-सम्मति की मुहर लगा सकेगा। सामाजिक कल्याण और आर्थिक उन्नति के स्वीकृत और प्रशसनीय उद्देश्य रखने के बावजूद कमीशन की वर्तमान योजनाओं को जनता का सहयोग या स्वीकृति नहीं मिल पाती, जैसे कि जनता के समर्थन

की वर्तमान मात्रा और उत्साह से दिखाई देता है।

कमीशन ने पिछले दशक में वास्तविक उद्देश्य और महत्ता के कार्यक्रम के कार्यान्वयन सगठनात्मक तथा प्रशासनात्मक बुनियादी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। इसके कार्यक्रम को नियंत्रित करनेवाली इसकी नीतियों, उनके प्राविधिक-आर्थिक तत्वों, और अर्थ-व्यवस्था के समग्र और स्थायी अंग के रूप में विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना और विकास के साथ उसकी सबद्धता तथा इनके प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण और अनुसन्धान के कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना अत्यावश्यक है, और इस पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से ही विचार करना चाहिए।

जैसा कि शुरू में ही बताया गया है, खादी केवल एक उपभोक्ता वस्तु नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धान्तों का पुज्य है। वे तथाकथित भावनात्मक मूल्य, जो खादी के साथ जोड़े जाते हैं, अक्सर भावुकता की उस सीमा तक उतर आते हैं, जहाँ खादी अपने निज के समस्त मूल्य ही खो बैठती है। खादी के सामाजिक उद्देश्य की मान्यता, जिसे गांधीजी अपनी सर्वश्रेष्ठ विरासत के रूप में राष्ट्र के पाम छोड़ गये हैं, उस प्रयास कार्यक्रम की तैयारी में

सहायक हो सकती है जो कि सब को आर्थिक रूप में स्वीकार्य होगा और सामाजिक रूप में वह इतना महत्वपूर्ण होगा कि सभी वर्ग के लोग इसमें स्वेच्छापूर्वक सहयोग दे सकेंगे।

हमारी जनता के ६० प्रतिशत से भी अधिक भाग की आय का निम्न स्तर और उसकी गरीबी के किसी तात्कालिक सुधार की क्षीण सभावनाएँ हमें सतत निर्भर रखनेवाले कार्यक्रमों अथवा स्थायी फल का आश्वासन न दे सकने योग्य कार्यकलापों की ओर न ले जा पाएँ इसका ध्यान हमें रखना होगा। दुर्भाग्य से ये दोनों ही सामाजिक-आर्थिक-संरचना में बुराईयाँ और सभाव्य राजनीतिक खतरा पैदा करते हैं। इस परिस्थिति को सुधारने की दृष्टि से जो परिवर्तन जरूरी हैं, वे इतने पर्याप्त होने चाहिए कि वर्तमान काल में जनता में प्रेरणा भर दे और उन्हें इस बात के लिए उत्साहित करे कि वे अपने प्रयत्नों को जारी रखें तो अतः सफलता मिलेगी ही। अगर यह लेख नीति तय करनेवाले लोगों को उपर्युक्त तरीकों से सोचने के लिए बाध्य कर सके, तो मेरा प्रयास सार्थक होगा।

बम्बई २१ अगस्त १९६१

अभय के मानी हैं बाहरी भयमात्र से मुक्ति-मौत का भय, धन दौलत लुट जाने का भय, कुटुंब परिवार विषयक भय, रोग भय, शस्त्रप्रहार का भय, प्रतिष्ठा का भय, किसी के बुरा मानने का भय।

— महात्मा गांधी

गत पन्द्रह वर्ष में रोजगारी व बेरोजगारी

भगवन्त नागेश दातार

दो योजनाएँ पूरी होने और तीसरी के चलने के बावजूद बेरोजगारी की स्थिति बदतर होती जा रही है, अर्थ-व्यवस्था का विकास जैसी कल्पना की गयी थी, उससे धीमा हो रहा है। पिछले पन्द्रह वर्ष में रोजगारी की क्या स्थिति रही है, उस पर तथा बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुत लेख में विचार किया गया है।

आयोजन और विकास के मन्दर्भ में रोजगारी का कितना महत्व है, इस बात पर जोर देने की शायद ही कोई आवश्यकता हो। काम चाहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति रोजगारी की स्थिति में अवश्य प्रभावित होता है। अगर उसे काम नहीं मिलता है, तो स्वयम् उसे तथा उसके परिवार को तो जीवन में कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है पर साथ-साथ राष्ट्र को भी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में राष्ट्र के उत्पादन कार्य में बिना हाथ बँटाए वस्तुओं का उपभोग होता है। देश में लोग अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण, सहज प्रवृत्ति और क्षमता या कौशल के अनुसार हजारों काम-धंधे करते हैं। कुछ लोग गाँवों में रहते हैं तो कुछ शहरों में और काम की खोज में वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साधारणतः गाँवों से शहरों में जाते हैं। यद्यपि काम की खोज करना व्यक्ति के लिए बड़ा सहज दीखता है, किन्तु उसे प्राप्त करना सदैव ही आसान नहीं होता। वस्तुतः आज रोजगारी पाने का वास्तविक संघर्ष चल रहा है, और इससे यह प्रश्न राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और आयोजक से लेकर साधारण व्यक्ति तक की गहरी और स्थायी दिलचस्पी का विषय बन जाता है।

अन्तर

आर्थिक विकास और रोजगारी के अवसर निर्माण करना, ये दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं जिसका ध्येय बेहतर जीवन व्यतीत करने की हमारी अनन्त आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। रोजगारी (यानी व्यक्ति जो दैनिक या मासिक पारिश्रमिक अथवा वेतन

अर्जित करते हुए काम करते हैं) और बेरोजगारी (यानी व्यक्ति जो काम में लगे थे पर बाद में बेरोजगार हो गये या वे व्यक्ति जो काम की तलाश में हैं) में जो अन्तर है वह बिल्कुल स्पष्ट है। ये विचार ऐसे काम से सम्बन्धित हैं जो पारिश्रमिक पर होता है और ऐसी विकसित अर्थ-व्यवस्था का वर्णन करने में प्रयोग में लाये जाते हैं, जहाँ के लोगों को या तो रोजगारी प्राप्त है या वे बेरोजगार हैं।

बेरोजगारी के कारण

विकसित अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी का मुख्य कारण तकनालाजिकल परिवर्तन होता है और वह अस्थायी होती है तथा व्यापार की स्थिति में सामान्य अर्थ में होनेवाले उतार-चढ़ाव पर और अभिनवीकरण एवं उत्पादन प्रक्रिया में उन्नत तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता के स्तर में हुए परिवर्तनों पर आधारित रहती है। विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में आयोजक को उत्पादकता और रोजगारी में वृद्धि करनेवाले तरीकों में सतुलन स्थापित करना पड़ता है। नये-नये उद्योगों और परियोजनाओं से रोजगारी के नये द्वार उन्मुक्त होते हैं। निरन्तर रोजगारी उपलब्ध करने और जनशक्ति बर्बाद जाने से रोकने के लिए प्रविस्तरण प्रबन्ध करने की आवश्यकता होती है। विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में अर्ध-बेरोजगार लोगों का भी खयाल करना पड़ता है, जो बिल्कुल बेकार तो नहीं हैं पर उनके पास पूरा काम नहीं होता और वे अतिरिक्त काम के लिए उपलब्ध हैं अर्थात् वे और भी काम कर सकते हैं।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देश में फिलहाल जैसी स्थिति है उसमें काफी लोग बेरोजगारी से प्रभावित हैं और उनसे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिन्हें आशिक रोजगारी ही प्राप्त है। यद्यपि गाँवों में पूर्ण और अर्ध बेकारी में अन्तर नहीं किया जा सकता, पर पूर्ण बेकारी की समस्या प्रायः शहरों में अधिक है और अर्ध बेकारी की गाँवों में। चूँकि काम करने की इच्छा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त काम नहीं मिल पाता, इसलिए जो-कुछ थोड़े-बहुत काम के अवसर उपलब्ध हैं काम करनेवालों में उनका बँटवारा हो जाता है। अगर इस अतिरिक्त जन-शक्ति को सक्रिय बना दिया जाय तो आर्थिक विकास बड़ी तीव्र गति से हो सकता है। यह कथन कि भारत में साधनों की प्रचुरता होते हुए भी गरीबी व्यापक रूप से व्याप्त है, शायद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एक ही साधन-स्रोत-जन-शक्ति-की ओर संकेत करता है।

गत १५ वर्षों में रोजगारी की स्थिति के मूल्यांकन का अर्थ है १९४७ यानी स्वतंत्रता-प्राप्ति के वर्ष से मूल्यांकन शुरू करना। इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई है जानकारी की कमी और अन्तर इतने विस्तृत हैं कि रोजगारी, बेरोजगारी और अर्ध रोजगारी की स्थिति का परिपूर्ण चित्र उपस्थित करना सम्भव नहीं है। सन् १९४७ और १९५० के बीच की अवधि ऐसी अवधि थी कि उसमें देश की शक्ति विभाजन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में ही लगी। अतः १९५१ की जन-गणना ही एक ऐसा साधन है जिस पर हम विश्लेषण करने के लिए निर्भर रह सकते हैं। किन्तु जन-गणना तो इस बात का अध्ययन करने में ही उपयोगी हो सकती है कि काम में लगे लोग किस प्रकार के काम करते हैं।

नगरी में रोजगारी

बेरोजगारी और वह भी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में जानकारी राष्ट्रीय रोजगारी सेवा के अन्तर्गत रोजगारी कार्यालयों के जरिये प्राप्त की जाती है। दिसम्बर १९४७ में रोजगारी कार्यालयों के पास करीब १ लाख ७२ हजार लोगों ने अपने नाम

दर्ज कराये थे और दिसम्बर १९५० में यह संख्या बढ़ कर २ लाख ८७ हजार हो गयी थी। रोजगारी और बेरोजगारी की स्थिति को समझने के लिए इन आकड़ों की व्याख्या अनेक सीमाओं यानी बातों से नियंत्रित होती है, जैसे रोजगारी कार्यालयों की कुछ चुनिन्दा स्थानों पर ही स्थापना, समय-समय पर इन कार्यालयों की संख्या में वृद्धि होना, इन कार्यालयों में स्वेच्छा से नाम दर्ज कराना और इनके जरिये काम दिलाना, काम में लगे लोगों द्वारा अच्छा काम पाने हेतु नाम दर्ज कराने की सम्भावना आदि। अतः ये आकड़े शहरों की बेरोजगारी की स्थिति से भी पूर्णतः अवगत नहीं कराते। यद्यपि इस अवधि में श्रम-शक्ति की वृद्धि और रोजगारी के सृजन का विवरण उपलब्ध नहीं है, पर यह मानना अनुचित न होगा कि १९४७ से १९५१ के बीच की अवधि में आर्थिक मामलों पर जो चर्चाएँ हुईं उनमें बेरोजगारी मुख्य विषय नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय महायुद्ध और कोरिया की लड़ाई के कारण बाजार में जो तेजी आयी थी, उससे रोजगारी की स्थिति में कुछ इस हद तक स्थिरता आयी कि वह अधिक चिन्ता-जनक नहीं थी।

दो योजनाओं में

अब प्रथम एवम् द्वितीय योजना-काल में परिमाण की दृष्टि से रोजगारी की स्थिति का मूल्यांकन करना समीचीन होगा। परिमाण की दृष्टि से रोजगारी की स्थिति को प्रभावित करनेवाले कारण हैं (अ) योजना के शुरू में बेरोजगारों की संख्या, (आ) योजनावधि में श्रम-शक्ति में वृद्धि, और (इ) योजना के कार्यान्वयन के परिणाम-स्वरूप अतिरिक्त रोजगारी के अवसरों का सृजन। अन्तिम (इ) के सम्बन्ध में अनुमान लगाते वक्त अर्थ-व्यवस्था के आयोजित विभाग में प्रत्यक्ष रूप से रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों की संख्या पर ही ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि उन लोगों की संख्या का भी ध्यान रखा जाता है जिन्हें परोक्ष रूप से व्यापार, वाणिज्य और यातायात के क्षेत्रों में रोजगारी उपलब्ध हुई है। श्रम-शक्ति में हुई वृद्धि की गणना लाभदायक रूप से काम

में लगे या काम पाने की कोशिश में लगे १५-५९ वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले स्त्री-पुरुषों के अनुपात में की जाती है।

प्रथम योजना

प्रथम योजना मुख्य रूप से महायुद्ध और देश के बँटवारे से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से बनायी गयी थी। उल्लिखित कारणों से इस योजना में रोजगारी की स्थिति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मोटे तौर पर प्रथम पंच वर्षीय योजना का उद्देश्य देश की अर्थ-व्यवस्था की बुनियाद मजबूत करना और आगामी वर्षों में विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए साम्प्रतिक परिवर्तन लाना था। परन्तु योजना के मध्य में योजना आयोग को बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान देना पड़ा। कोरिया की लड़ाई से उत्पन्न तेजी के गिरते ही काम चाहनेवालों की संख्या में वृद्धि होने लगी और दिसम्बर १९५३ में रोजगारी कार्यालयों के पास काम चाहनेवालों के नामों की संख्या करीब ५ लाख २२ हजार तक पहुँच गयी। अतः बेरोजगार लोगों को काम देने के उद्देश्य से विशिष्ट योजनाएँ सम्मिलित करने हेतु योजना में संशोधन किया गया। ऐसी अल्प-कालीन योजनाएँ सम्मिलित की गयीं, जिनसे रोजगारी के सृजन को प्रोत्साहन मिले। आरम्भ में प्रथम योजना में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में ५५ लाख लोगों को काम उपलब्ध कराने का लक्ष्य था।

योजनावधि में 'एक दश-सूत्री कार्यक्रम' सहित और जो कार्यक्रम शुरू किये गये उनके फलस्वरूप प्रथम योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य लगभग प्राप्त हो गये। किन्तु प्रथम योजना में जितने नये काम करनेवालों की संख्या बढ़ी थी उसके हिसाब से यह लक्ष्य भी कम था। बाद में रोजगारी की स्थिति बिगड़ी और इसका पता इस बात से लग जाता है कि मार्च १९५६ तक रोजगारी कार्यालयों के रिक्रजिस्टर, (लाइव रजिस्टर) के नाम दर्ज करानेवाले बेरोजगारों की संख्या ७ लाख ५ हजार तक पहुँच गयी। इन पाँच वर्षों में (मार्च १९५१ से मार्च १९५६ तक की अवधि में) विशुद्ध वृद्धि ३ लाख

६८ हजार थी। इन आकड़ों का अध्ययन यदि शहरो की बेकारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (प्रारम्भिक सर्वेक्षण) में प्राप्त परिणामों को दृष्टिगत रख कर किया जाय तो (सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ २५ प्रति शत बेकार लोग ही अपना नाम रोजगारी कार्यालयों में दर्ज कराते हैं) १९५१ और १९५६ में मौजूदा बेकारी की हालत का मोटे तौर पर अन्दाज लगाया जा सकता है। शायद इनकी संख्या क्रमशः १३ लाख ४८ हजार और २८ लाख २० हजार हो सकती है।

द्वितीय योजना

इस आधार पर द्वितीय योजना के प्रारम्भ में अस्थायी बेकारी को छोड़ कर—जिनका होना अपरिहार्य है—२५ लाख बेरोजगार लोगों का अनुमान लगाया गया। कृषि श्रमिक जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर गाँवों में बेरोजगारों की संख्या का अनुमान २८ लाख लगाया गया था। रोजगारी प्रदान करना द्वितीय योजना का चार लक्ष्यों में से एक था। इस समस्या को भली-भाँति समझने हेतु द्वितीय योजना-काल में नियमित रूप से रोजगारी विषयक जानकारी एकत्रित करनेवाला संगठन काफी शक्तिशाली बनाया गया, नये रोजगारी कार्यालय स्थापित किये गये और इन कार्यालयों द्वारा चलाये जानेवाले रोजगारी के विषय में सूचना देनेवाले केन्द्रों का एक जाल-सा बिछाया गया। ये केन्द्र ऐसे सार्वजनिक एवम् गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में, जिनमें से प्रत्येक में २५ या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, रोजगारी की हालत की खबरे देने लगे। और, प्रत्येक केन्द्र ने विभिन्न स्थानों पर रोजगारी की स्थिति में होनेवाले परिवर्तनों के बारे में उपयोगी सामग्री प्रदान की।

दूसरी योजना के प्रारम्भ में देश में ५३ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, जिनमें से २५ लाख शहरो में व २८ लाख गाँवों में थे। यह अनुमान था कि दूसरी योजना की अवधि में काम चाहनेवाले नये एक करोड़ लोग आ जायेंगे। पूर्ण रोजगारी देने के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में १ करोड़ ५० लाख से

अधिक लोगों को काम देना आवश्यक था। यह स्वीकार किया गया था कि योजनावधि में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिए कम से कम उन लोगों को जो प्रति वर्ष काम पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, काम दिलाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि बेरोजगारी की स्थिति जहाँ की वहाँ रोक रखी जाय। अतः दूसरी पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य करीब एक करोड़ लोगों को काम दिलाना रखा गया। यह अपेक्षा की गयी थी कि सिंचाई, सामुदायिक विकास, ग्राम एवम् लघु उद्योगों आदि सम्बन्धी कार्यक्रमों के जरिये अर्ध बेकारों को भी कुछ राहत मिल जायगी। इसके अतिरिक्त शिक्षित बेकारों के लिए कुछ विशेष योजनाएँ बनायी गयी, जैसे कार्य-सह-अभिस्थापन केन्द्रों, सहकारी भारवाही यातायात, उत्पादन केन्द्रों आदि की स्थापना।

रोजगारों की संख्या में वृद्धि

तथापि, योजना के परिव्यय और स्थूल लक्ष्यों में संशोधन करके कमी करनी पड़ी और साथ ही कीमते बढ़ी जिससे योजना के लिए निर्धारित रोजगारी के अवसरों में २० प्रति शत की कमी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि तीसरी योजना के प्रारम्भ में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ओर भी बढ़ी हुई थी। प्रथम और द्वितीय योजनाओं में रोजगारी के अवसर निर्मित करने में काफी प्रयत्न करने के बावजूद उनकी समाप्ति पर देश में बेकारों की संख्या बढ़ी। अनुमानतः उस समय करीब ९० लाख लोग बेकार थे, जिन्हें रोजगारी देने का काम तृतीय और उसके बाद की योजनाओं पर छोड़ा गया। यह संख्या देश की कुल ४३ करोड़ ९० लाख जन-संख्या का करीब २१ प्रति शत है।

बेरोजगारों की इतनी बड़ी संख्या होने के अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया था कि तृतीय योजना की अवधि में करीब १ करोड़ ७० लाख व्यक्ति नये काम करनेवाले तैयार हो जायेंगे और १९६१ की जन-गणना के आकड़ों के हिसाब से—जिन्हें अभी सारिणीबद्ध किया जा रहा है—जब इस संख्या में संशोधन किया जायगा तो बहुत सम्भव है कि यह और भी बढ़ जाय। यद्यपि अर्ध-

बेकारी की अवस्था का सही-सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, पर ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास थोड़ा ही काम है और वे अधिक काम पाने के लिए इच्छुक हैं, आज १ करोड़ ५० लाख से १ करोड़ ८० लाख तक मानी जाती है। यह अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा १९५५ और १९५७ के मध्य की गयी जाँचों पर आधारित है और यह उन लोगों से सम्बन्धित है, जिन्हें औसतन दैनिक चार घण्टा या उससे कुछ कम समय तक ही काम मिल पाता है (वे बुरी तरह अर्ध बेकारी के शिकार हैं) तथा उन लोगों से जो प्रति दिन ४ घण्टे से ८ घण्टे तक काम कर लेते हैं (साधारणतः अर्ध बेकार लोग) किन्तु अधिक काम पाने के इच्छुक हैं। तृतीय योजना का लक्ष्य १ करोड़ ७० लाख व्यक्तियों के लिए काम के अवसर निर्मित करना है, जोकि अपेक्षित नयी श्रम-शक्ति की वृद्धि के बराबर ही है।

तृतीय योजना में इस समस्या के विभिन्न पहलुओं और रोजगारी का लक्ष्य प्राप्त करने के कल्पित उपायों पर भी व्यापक रूप से विवेचन किया गया है। इसका उद्देश्य १ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों को रोजगारी देने की व्यवस्था करना है—जिनमें से १ करोड़ ५ लाख को गैर कृषि क्षेत्र में और ३५ लाख को कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों में। योजना के अंतिम वर्ष में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों द्वारा गाँवों में योजना के अन्तिम वर्ष तक २५ लाख व्यक्तियों को काम देने की व्यवस्था भी की गयी है, परन्तु यह कार्यक्रम मुख्यतः अर्ध बेकारों को राहत देने के रूप में ही होगा। ग्रामीण और लघु उद्योगों, उनकी उत्पादक-क्षमता का पूर्ण उपयोग, ग्रामीण औद्योगीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, यातायात आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों को रोजगारी के अवसर निर्मित करने की दृष्टि से बहुत महत्व दिया जाता है।

ग्राम, खण्ड और जिला स्तरों पर बेरोजगारी की समस्या को हल करने पर भी योजना पर्याप्त जोर देती है। पहले की तरह यह बताया जा चुका है कि बेरोजगारी

निवारण की प्रक्रिया एक लम्बे अर्से तक चलनेवाली प्रक्रिया है। योजना में रोजगारी का एक दीर्घ-कालीन उद्देश्य यह है कि १९७६ तक कृषि पर निर्भर रहनेवाली श्रम-शक्ति का अनुपात घटा कर ६० प्रति शत कर दिया जाय। इसका यह अर्थ है कि १९६१-१९७६ की अवधि में गैरकृषि क्षेत्र में ५ करोड़ व्यक्तियों को काम देने की व्यवस्था की जाय।

मन्द आर्थिक विकास

तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में रोजगारी मुहैया करने का जो कम रहा है उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि अमूमन तौर पर श्रम-शक्ति में ३० लाख नये व्यक्ति वार्षिक रूप से काम चाहने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके समकक्ष ४० लाख को काम देने की व्यवस्था की गयी होती। स्पष्टतः प्राप्त मफलता हमारी आवश्यकता में ओछी पड़ती है। रोजगारी कार्यालयों में नाम दर्ज व्यक्तियों की संख्या में भी उक्त स्थिति का प्रतिबिम्ब मिलता है। उनकी संख्या मार्च १९६१ के अन्त में १५ लाख ६१ हजार थी जो मार्च १९६२ में १८ लाख ५४ हजार तक और मार्च १९६३ में तकरीबन २५ लाख तक पहुँच गयी। इस बात के लिए कुछ रियायत करते हुए भी कि रोजगारी कार्यालयों की संख्या में कुछ वृद्धि और रिक्त स्थानों को अनिवार्य रूप से अधिसूचित करने का कुछ प्रभाव पड़ा हो, तो भी इतनी अधिक वृद्धि वस्तुतः गहरी चिन्ता का विषय है।

कुल मिला कर देखने पर यह कहा जा सकता है कि जिस गति से आर्थिक विकास होने की कल्पना की गयी थी, उससे उसकी गति काफी कम रही है। राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आकड़ों से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। कृषि उत्पादन प्रायः स्थिर रहा है। शक्ति, कच्ची सामग्री, विदेशी विनिमय आदि की कमी जैसी अनेक बाधाओं के कारण उद्योग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। यदि जन-संख्या वृद्धि १९५१-६१ की दर से जारी रहती है तथा विकास की गति भविष्य में तीव्र नहीं हुई, तो यह मानने के कारण है कि तृतीय योजना के दरमियान रोजगारी की स्थिति और भी खराब हो जायेगी।

इसके साथ ही साथ कि बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती है, दूसरी तरफ जन-शक्ति की-विशेष कर तकनीकल और वृत्तिक कार्यकर्ताओं के मामले में-कमी है। किसी हद तक यह बात क्षेत्रीय असंतुलन के कारण हो सकती है, लेकिन समग्र रूप से देखने पर पता चलता है कि अर्थ-व्यवस्था की जन-शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा जन-शक्ति की पूर्ति के बीच सतुलन की कमी शायद अस्थायी है। तदनुसार तृतीय योजना में प्राविधिक शिक्षा के पर्याप्त विस्तार और प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था है, ताकि वर्तमान आवश्यकताएँ पूर्ण की जा सकें एवम् भविष्य में सभी स्तरों पर इस प्रकार के व्यक्तियों की उपयुक्त पूर्ति के लिए नीव डाली जा सके। देश के अन्दर ही प्रशिक्षित तकनीकल व्यक्ति तैयार करना, जन-शक्ति उपयोगिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुछ समय के लिए उधार लिये गये व्यक्तियों से काम चलाना सम्भव है, पर चूँकि प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी संसार में कमी है, इसलिए अनवरत रूप से उन्हें बाहर से बुलाते रहना न तो वाछनीय है और न शक्य ही।

गत बारह वर्ष में हमारी बेरोजगारी के एक दूसरे पहलू-शिक्षित बेरोजगारों-की तरफ देश का ध्यान गया है। रोजगारी कार्यालयों के रजिस्ट्रो से पता चलता है कि शिक्षित व्यक्ति पर्याप्त संख्या में बेरोजगार हैं। इस मामले में छानबीन करने की आवश्यकता है। सन् १९५५ में नियुक्त एक अध्ययन दल के अनुमान के मुताबिक-जिसने उन व्यक्तियों को शिक्षित माना था, जो मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे-द्वितीय योजना के प्रारम्भ में बेरोजगारी की संख्या ५ लाख ५० हजार थी। तब से इस संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस अध्ययन का एक परिणाम यह निकला कि इसने विश्व विद्यालय के स्तर की शिक्षा और रोजगारी के मध्य सम्बन्ध मालूम यानी स्थापित करने के विचार का प्रचलन किया, ताकि उस दिशा की खोज की जा सके, जिसमें शिक्षा का अभिनवीकरण करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में प्रथम कदम यह था कि दिल्ली विश्व विद्यालय से १९५० और १९५४ में निकले विद्यार्थियों

का १९५८-५९ में एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने उक्त वर्षों में स्नातकीय उपाधियाँ, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त किये। यद्यपि ऐसा लगता है कि सर्व प्रथम रोजगारी मिलने से पहले उक्त विद्यार्थियों में से बहु-सो को एक वर्ष तक बेरोजगार रहना पड़ा, किन्तु समग्र रूप से देखने पर उनकी रोजगारी सम्बन्धी स्थिति असन्तोषजनक नहीं पायी गयी। उनमें से अधिकांश को सार्वजनिक विभाग में काम मिला। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि अधिक वेतन, पेशे की दृष्टि से उच्च दर्जे अथवा अधिक सुरक्षा की खोज के लिए उनमें पर्याप्त तत्परता थी।

वृत्तिक उद्देश्यविहीनता के अत्यधिक प्रभाव के अतिरिक्त रोजगारी प्राप्त करने में पारिवारिक पद्धति का अनुसरण करने की ओर शक्तिशाली झुकाव था। महिला विद्यार्थियों में शिक्षण-कार्य सर्वाधिक लोकप्रिय था— करीब ५० प्रति शत स्थानों पर वे काम कर रही थी। सर्वेक्षण से इस बात का पता चला कि कानूनी पढाई के अतिरिक्त वृत्तिक तथा प्राविधिक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में शिक्षा और रोजगारी के मध्य निकट सम्बन्ध है। सामान्य शिक्षा प्राप्त अधिकांश व्यक्ति क्लर्की का काम करते पाये गये, जिससे सामान्य शिक्षा और रोजगार के मध्य असतोषजनक सम्बन्ध की स्थिति प्रकाश में आयी। सामान्य स्नातकीय प्रमाण-पत्रो-वाले व्यक्तियों में पर्याप्त पेशेवर सक्रियता, तत्परता पायी गयी। दिल्ली सर्वेक्षण (१९५८-५९ में) के परिणामों से प्रोत्साहित हो कर स्नातकीय रोजगारी की पद्धति पर १९६० में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया, जो उन विश्वविद्यालयीन स्नातकों तक ही सीमित था, जिन्होंने १९५० और १९५४ में डिग्रियाँ प्राप्त की। यद्यपि इस द्वितीय सर्वेक्षण के अंतिम आकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो भी सारांश रूप में अखिल भारतीय आकड़ों से दिल्ली सर्वेक्षण के निष्कर्षों का समर्थन होता प्रतीत होता है।

इन सर्वेक्षणों तथा विकसित किये जानेवाले उद्योगों और अनुमानित जन-संयोजन पद्धति के आधार पर उनकी आवश्यकताओं के बारे में सहायक जानकारी से शिक्षित जन-शक्ति की बेहतर उपयोगिता के लिए सुझाव प्राप्त होगा। ज्यों-ज्यों योजना में प्रगति होती है, त्यों-त्यों ग्राम प्रशासन, शिक्षा, उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगारी के अधिकाधिक अवसरों का सृजन भी होनेवाला है। अधिक रोजगारी के अवसर निर्मित करने और साथ ही साथ शारीरिक श्रम करने प्रति उनके दृष्टिकोण में अन्तर आने से उनकी समस्या हल करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसमें प्रकट होगा कि

१ भारत में रोजगारी की समस्या का तात्पर्य है पूर्ण और अल्प-बेरोजगारी—प्रथम मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में और द्वितीय ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती है।

२ स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर १९५१ तक आर्थिक मामलों पर हुए विचार में रोजगारी का सवाल महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध और कोरिया की लड़ाई के कारण आयी तेजी का अनुकूल प्रभाव पड़ा।

३ प्रथम दोनों तथा तृतीय योजनाओं के अन्तर्गत विकासशील प्रयत्नों के बावजूद रोजगारी की स्थिति में ह्रास होने के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, क्योंकि रोजगारी का उस तीव्र गति से सृजन नहीं हो रहा है कि श्रम-शक्ति में नवागतों को काम दिया जा सके।

४ यह एक विरोधाभास ही है कि पर्याप्त जन-शक्ति के होते हुए भी प्राविधिक तथा वृत्तिक व्यक्तियों के मामले में अर्थ-व्यवस्था के सामने जन-शक्ति की कमी आयी है। इसका अर्थ है देश में जन-शक्ति की आवश्यकता व उसकी पूर्ति के बीच सन्तुलन का अभाव—सम्भवतः अस्थायी।

५ सामान्य बेरोजगारी के साथ ही साथ शिक्षित व्यक्तियों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है।

नयी दिल्ली ७ मितम्बर १९६३

भारत में पूँजी संचयन और निवेश

अमृतलाल दत्त

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् सकल अचल निवेश की वृद्धि दर सकल राष्ट्रीय उत्पादन की दर से तीव्र रही है। पूँजी संचयन की वार्षिक वृद्धि दर भी विशुद्ध अचल निवेश की दर से आगे बढ़ गयी है। ऐसा, उच्च वृद्धिशील पूँजी-उत्पादन-अनुपात के साथ साथ हुआ है। प्रस्तुत लेख में बताया गया है कि निर्यात-आय को अधिकतम बनाया जाय। उससे ही देश में अचल पूँजी निर्माण की प्रक्रिया को द्रुत गति मिल सकनी है।

भारत में पूँजी निर्माण का विकास काफी समय में मन्द रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में दीर्घ स्तर पर विनियोजन करके जूट और वस्त्रोद्योग की स्थापना को छोड़ कर १९२० या १९३० तक देश में औद्योगिक विकास प्रायः गतिहीन ही रहा। उक्त समय में यानी १९२०-३० के बीच उपभोक्ता सामग्री तथा अन्य कुछ मध्यस्थ-सूष्ठ (अर्थात् ऐसे उत्पादन जो प्राथमिक भी न हों और अन्तिम भी न हों, बल्कि बीच-वाले, जैसे पूनी) उत्पादन के लिए चन्द उद्योग स्थापित हुए। युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में इस प्रक्रिया को कुछ बढ़ावा मिला और डीजल इंजन, रेल के इंजन, वस्त्रोद्योगी यंत्र आदि का निर्माण करनेवाले बुनियादी सामग्री उत्पादक उद्योगों की स्थापना करने हेतु एक श्रीगणेश भी हुआ। तथापि, विनियोजन न केवल उपभोक्ता सामग्री उद्योगों में ही सकेन्द्रित था, बल्कि उसका नियन्त्रण और प्रबन्ध भी प्रायः परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यक्तियों के हाथ में था। अनेक सर्वविदित बाधक पहलुओं के कारण बुनियादी सामग्री उत्पादक उद्योगों के विस्तार की सीमित गुंजाइश थी। परिणाम-स्वरूप अचल विनियोजन अर्थात् निवेश के लिए निर्धारित साधन-स्रोत अपेक्षाकृत मामूली थे।

देश को आजादी मिलने के साथ अचल सम्पत्ति निर्माण की दीर्घ-कालीन गतिहीनता समाप्त हुई।

अगस्त १९४७ के पश्चात् का समय भारत के आर्थिक विकास में एक नये उत्साहपूर्ण अध्याय के प्रारम्भ का द्योतक है। औद्योगिक नीति में परिवर्तन और पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ के साथ सरकारी नीति अधिक तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए अधिकाधिक रूप से अचल निवेश यानी विनियोजन के विस्तार की ओर उन्मुख हुई। पिछले वर्षों में देश ने कितनी तीव्र प्रगति की है, इस बात की एक झलक आजादी हासिल करने के बाद अचल सम्पत्ति निर्माण में कितना विकास हुआ है उससे प्राप्त की जा सकती है। सन् १९४८-४९ और १९६०-६१ के बीच जहाँ सकल अचल सम्पत्ति सात प्रति शत वार्षिक की दर से बढ़ी वहाँ सार्वजनिक विकास में यह वृद्धि १३ प्रति शत थी और निजी विभाग में ५६ प्रति शत। इसके अलावा समग्र अचल निवेश में सार्वजनिक विकास का हिस्सा (१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर) योजना-युग से पूर्व १९३ प्रति शत था, वह प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः २७३ और ३५५ प्रति शत हो गया। निवेश के इस परिमाण में हुई वृद्धि के साथ सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सकल अचल निवेश की वृद्धि (यानी औसत निवेश अनुपात) भी हुई। जैसा कि निम्न आकड़ों से प्रकट है, योजना-पूर्व-काल का औसत निवेश अनुपात

टिप्पणी प्रस्तुत लेख लेखक ने व्यक्तिगत हैसियत से लिखा है।

प्रथम योजना में १२१ से बढ़ कर १३२ प्रति शत और द्वितीय योजना में १७५ प्रति शत हो गया।*

सकल अचल मे वार्षिक वृद्धि की दर (प्रातिशत्य)	निवेश औसत निवेश अनुपात
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर)	
योजना-पूर्व काल	
(१९४८-४९ से १९५०-५१)	४१ १२१
प्रथम योजना काल	
(१९५१-५२ से १९५५-५६)	८६ १३२
द्वितीय योजना काल	
(१९५६-५७ से १९६०-६१)	६५ १७५
समग्र काल	
(१९४८-४९ से १९६०-६१)	७.० १४८

स्रोत भागत मरकार केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ एशिया और सुदूर पूर्व का आर्थिक संवर्क्षण, १९६१।

निवेश हेतु साधन-स्रोतों का नियतन फिर भी अधरुण योजना-कालों का पालन नहीं करता। इस बात का पता निवेश अनुपात के झुकाव से लग सकता है, जोकि १९५४-५५ तक प्रायः स्थिर ही रहा, किन्तु उसके बाद उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जैसा कि आगे तालिका १ में दिये गये अंकों से पता चलता है स्थिर मूल्यों के आधार पर औसत निवेश-अनुपात में सुधार हुआ और वह १९४८-४९/१९५४-५५ के दरमियान के १२३ प्रति शत से बढ़ कर १९५४-५५/१९६०-६१ के दौरान १६६ प्रति शत हुआ। मन् १९५४-५५ के पश्चात् न केवल सार्वजनिक परिव्यय तीव्र ब्रनाया गया बल्कि निजी क्षेत्र में भी अधिक कार्यशीलताओं।

* इस सम्पूर्ण लेख में अचल निवेश, स्टाक तथा अन्य सहायक आकड़े 'राष्ट्रीय आय सांख्यिकी' (भारत में १९४८-४९ से १९६०-६१ तक सकल पूँजी निर्माण का अनुमान) पर प्रकाशित केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन के 'पेपर' से लिये गये हैं।

ने जोर पकड़ा, जिसे कि आजादी मिलने से पहले के प्रारम्भिक काल की अनिश्चितता के वातावरण (राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों के झगड़ों आदि का भय) की वजाय अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में अब अधिक विश्वास हो गया था। फिर भी, १९५४-५५ से सकल अचल निवेश की वृद्धि की दर सकल राष्ट्रीय उत्पादन विकास से अधिक रही है। जहाँ १९४८-४९ से १९५४-५५ तक अचल निवेश में वृद्धि की औसत दर ५३ प्रति शत और १९५४-५५ से १९६०-६१ तक ८७ प्रति शत रही है, वहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पादन की उक्त अवधियों के लिए औसत दर क्रमशः २९ प्रति शत तथा ३१ प्रति शत रही है। अतएव अव्ययन के उद्देश्य से १९५४-५५ को निर्माजक रेखा माना जा सकता है।

भारत में जिन दो विभागों ने अचल वित्तियोजन व्यवसा निवेश के विकास में योगदान दिया उनमें निजी विभाग ने—जैसा कि उरकी भूत कालीन देन का निदर्शन किया गया है—सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सार्वजनिक विभाग के अपेक्षाकृत मामूली हिस्से (४३ प्रति शत) के समक्ष काफी अधिक (१०५ प्रति शत) योगदान दिया। फिर भी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है अचल निवेश में वार्षिक वृद्धि की दर निजी विभाग की अपेक्षा सार्वजनिक विभाग में काफी अधिक थी, आलोच्य काल के उत्तरार्द्ध में अनुवर्ती की दर में कुछ कमी आयी तो पूर्ववर्ती की दर में पर्याप्त सुधार हुआ। तथापि, आलोच्य काल में सार्वजनिक विभाग के सम्बन्ध में जो समस्त रूप से उच्च दर दृष्टिगोचर होती है वह इस बात का प्रमाण है (यदि प्रमाण की आवश्यकता भी हो तो) कि आजादी के बाद इस विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका जो न्यून निवेश अनुपात है उसे भी १९३०-४० के मध्य सार्वजनिक आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो गतिहीनता की अवस्था थी, उनके सन्दर्भ में प्रभावोत्पादक समझा जा सकता है। (नीचे तालिका २ देखिए)

तालिका १
सार्वजनिक और निजी निवेश की प्रगति
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सकल अचल निवेश का अनुपात			सकल निवेश में सार्वजनिक निवेश का प्रातिशत्य
	सार्वजनिक	निजी	कुल	
१९४८-४९	२१	९५	११६	१७९
१९४९-५०	२३	१०१	१२४	१८९
१९५०-५१	२६	९७	१२३	२१०
१९५१-५२	२०	१००	१२९	२२३
१९५२-५३	२९	९२	१२१	२४०
१९५३-५४	३२	८६	११८	२७२
१९५४-५५	३८	७४	१३२	२९२
१९५५-५६	५०	१०६	१५६	३१८
१९५६-५७	५४	११९	१७३	३११
१९५७-५८	५४	१३३	१८७	२९०
१९५८-५९	५३	११२	१६६	३२१
१९५९-६०	७३	१०८	१७१	४२८
१९६०-६१	५८	१२०	१७८	३२४

स्रोत : अचल निवेश के सम्बन्ध में आकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय मण्डल के 'पेपर' से और सकल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में संयुक्त राष्ट्र मण्डल द्वारा १९६१ में किये गये 'एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक सर्वेक्षण' से लिये गये हैं। द्वितीय आकड़े प्रथम से सकलित किये गये हैं।

तालिका २
सकल राष्ट्रीय उत्पादन और सकल अचल पूँजी निर्माण के विकास में सम्बन्ध
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

वार्षिक वृद्धि दर (प्रातिशत्य)	१९४८-४९ से १९६०-६१ तक	१९४८-४९ से १९५४-५५ तक	१९५४-५५ से १९६०-६१ तक
सकल राष्ट्रीय उत्पादन (स रा उ)	३०	२९	३१
सकल अचल निवेश (स अ नि)	७०	५३	८७
१. सार्वजनिक क्षेत्र	१३.०	१४.२	११.८
२. निजी क्षेत्र	५.६	२७	८५
स. रा उ. के प्रातिशत्य स्वरूप (स अ नि.)	१४.८	१२.३	१६.६
इसमें १ सार्वजनिक क्षेत्र	४.३	२९	५५
२. निजी क्षेत्र	१०.५	९४	११.१
वृद्धिशील पूँजी-गुणक अनुपात *	४९	४२	५४

* औसत निवेश अनुपात को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर से भाग देकर निकाला गया।

आलोच्य काल में सकल और विशुद्ध निवेश के निवेश के परिवर्तनों में अन्तर माल (स्टॉक) की पारस्परिक सम्बन्ध में परिवर्तनों तथा वस्तु-सूचियों स्फीतियों के कारण थे जो १३ प्रति शत से बढ़ कर १५ प्रति शत हो गयी। इसका मुख्य कारण था, देश में परिवर्तन व अवमूल्यन का अध्ययन करना यहाँ रुचि- १५ प्रति शत हो गयी। इसका मुख्य कारण था, देश में फसलों का अनिश्चित होना जिससे आयात के कुछ समझन (जैसा कि तालिका की टिप्पणी में बताया जा रहा है) किया गया है, फिर भी यह माना जा सकता है कि जरिये खाद्यान्नों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति सकल और विशुद्ध

तालिका ३

सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रातिशत्य स्वरूप सकल अचल निवेश, अवमूल्यन, वस्तु-सूची और पूँजी संचयन में सापेक्षिक परिवर्तन (१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

अवधि	सकल अचल निवेश	अवमूल्यन	विशुद्ध अचल निवेश	वस्तु-सूची परिवर्तन	पूँजी संचयन
१९४८-४९ से १९५०-५१	१२१	७६	४५	११	५६
१९५०-५१ से १९५२-५३	१२४	७३	५१	१०	६१
१९५२-५३ से १९५४-५५	१२४	६९	५५	११	६६
१९५४-५५ से १९५६-५७	१५४	६७	८७	१८	१०५
१९५६-५७ से १९५८-५९	१७५	६५	११०	१७	१२७
१९५८-५९ से १९६०-६१	१७२	६४	१०८	२१	१२९
१९४८-४९ से १९६०-६१	१४८	६९	७९	१४	९३
१९४८-४९ से १९५४-५५	१२३	७३	५०	१३	६३
१९५४-५५ से १९६०-६१	१६६	६५	१०१	१५	११६

टिप्पणी चूंकि विशुद्ध अचल निवेश के सम्बन्ध में प्रचलित मूल्यों के आधार पर आकड़े उपलब्ध हैं, इसलिए स्थिर मूल्यों के आधार पर विशुद्ध अचल निवेश हासिल करने के लिए प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए सकल अचल निवेश के प्रति विशुद्ध अचल निवेश का अनुपात स्थिर मूल्यों (१९५८-५९) के आधार पर सकल अचल निवेश पर लागू किया गया है।

स्रोत भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

है कि इस समझन से वस्तुस्थिति के झुकाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़नेवाला है। तालिका ३ से पता चल सकता है कि आलोच्य अवधि में सकल अचल निवेश और पूँजी संचयन दोनों की ही समान रूप से प्रतिक्रिया हुई। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुपात स्वरूप सकल तथा विशुद्ध दोनों ही प्रकार का अचल निवेश पूर्वार्ध में क्रमशः १२३ और ५ प्रति शत था जो उत्तरार्ध में बढ़ कर १६६ और १०१ प्रति शत हो गया। पूँजी संचयन में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई—वह ६३ से ११६ प्रति शत हुआ। पूँजी संचयन तथा विशुद्ध अचल

अचल निवेश के मध्य भारी अन्तर अवमूल्यन में परिवर्तन प्रतिबिम्बित करते हैं, जो पूर्वार्ध में ७३ प्रति शत था तथा उत्तरार्ध में घट कर ६५ प्रति शत हुआ। जहाँ समूची अवधि में विशुद्ध अचल निवेश सकल अचल निवेश की दर (७ प्रति शत) से काफी अधिक दर (१३७ प्रति शत) से बढ़े, वहाँ अवमूल्यन की वृद्धि १२ प्रति शत वार्षिक की नगण्य दर (तालिका ४) से बढ़े। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति अवमूल्यन का अनुपात पूर्वार्ध में विशुद्ध अचल निवेश के अनुपात से अधिक था, लेकिन उत्तरार्ध में वह उससे कम हो गया।

अवमूल्यन का सापेक्षिक रूप में कम अनुपात पूँजी-परिसम्पत्ति की दीर्घायु प्रतिबिम्बित करता है। युद्ध-कालीन टूटे-फूटे, घिसे बिमाये पुराने यंत्रों तथा सगन्ना के कारण पूर्वार्ध में उनकी व्यवहार लोपोन्मुखता यानी उनका अप्रचलन उत्तरार्ध की अपेक्षा अधिक था, जबकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में उन्हें हमबन्त बनाने की क्रिया के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में नये यंत्र और सयंत्र स्थापित किये गये।

तालिका ४

सकल अचल निवेश, अवमूल्यन, विशुद्ध अचल निवेश और पूँजी संचयन में वार्षिक वृद्धि दर का प्रारंभिक (१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

मद	१९४८ से १९४८-४९ में	१९४८-४९ से १९५४-५५ में	१९५४-५५ से १९६०-६१ में
सकल अचल निवेश	७०	५३	८७
अवमूल्यन	१२	११	१३
विशुद्ध अचल निवेश	१३७	१२३	१५२
पूँजी संचयन	१५४	१४२	१६६

स्रोत : भारत सरकार केन्द्रीय गणितीय सगठन।

पूँजी संचयन

उत्तरार्ध में पूँजी संचयन में न केवल वृद्धि ही हुई वरन् उसकी वार्षिक वृद्धि दर विशुद्ध अचल निवेश की वार्षिक वृद्धि दर को भी मात कर गयी। यद्यपि पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में अवमूल्यन में तनिक वृद्धि थी, पर वस्तु-सूचियों में परिवर्तन प्रायः नगण्य-सा ही रहा। इससे परमावश्यक माल की अपेक्षा कुछ अधिक माल का स्टॉक रखने के बावत औद्योगिक विभाग की असमर्थता प्रकट होती है। इसका मुख्य कारण था १९५७ में आये विदेशी विनिमय के मकट के कारण सीमित स्तर पर कच्चे माल के 'कोटा' का निर्धारण और कठोर आयात नियंत्रण। और फिर, आयात नियंत्रण, टैरिफ तथा अन्य ऐसे कारणों से बाजार बहुत ही सुरक्षित था, जिससे उत्पादक भारी मुनाफे पर

आना माल जल्दी-जल्दी खाली करने में समर्थ हुए। तथापि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि उत्तरार्ध में केन्द्रीय गोदामों में माल के स्टॉक में जो थोड़ी-बहुत वृद्धि थी वह खाद्यान्नों के मामले में किसी सकट काल का सामना करने के कारण हुई थी। प्राप्य पूर्ण के प्रति खाद्यान्नों के कुल स्टॉक का अनुपात १९४८-४९/१९५४-५५ के ६ प्रति शत से बढ़ कर १९५४-५५/१९६०-६१ के दोरान १६ प्रति शत हो गया (विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ ८६ पर तालिका १० देखिए)। फिर भी, स्टॉक में कुछ वृद्धि होने हुए भी उत्तरार्ध में पूँजी संचयन में तीव्र वृद्धि हुई। इस प्रकार अधिकाधिक अनुपात में मावामानों की प्रयुक्त निवेश को बढ़ावा और जा गदी हासिल करने के बाव तैरह वर्ष की लघु-कालीन अवधि में, दोरान अर्थ-व्यवस्था के तीव्र विकास को प्रशय गिरा। तथापि अर्थ-व्यवस्था के इस विस्तार में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों का हाथ रहा है, फिर भी सार्वजनिक विभाग ने जो गति हासिल की वह बहुत ही गभावशाली रही है।

इतना होने पर भी आलोच्यावधि के दरमियान पूँजी संचयन में अधिकांश बढ़ोतरी उच्च वृद्धिशील पूँजी-उत्पादन अनुपात के समकालीन अर्थात् उसके माप हुई है। जैसा कि पीछे तालिका २ में प्रस्तुत आकड़ों से पता चलता है, वृद्धिशील पूँजी-उत्पादन-अनुपात पूर्वार्ध के ४२ से बढ़ कर उत्तरार्ध में ५४ हो गया और उसके साथ ही सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति अचल निवेश का अनुपात भी उसी काल में १२३ से बढ़ कर १६६ हो गया था। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि उद्योग तथा कृषि दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भिक काल में अपने क्षमता-स्तर से काफी नीचे रहे और प्रायः करके माल तथा सेवाओं की कमी रही। यद्यपि बाद के वर्षों में उपलब्ध रसद सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ, किन्तु उसके यानी सामान के सगबन्ध में माग और भी अधिक बढ़ गयी है। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में माग के कारण घरेलू उपभोग तथा निर्यात विभाग के लिए वस्तुओं की

सप्लाई में विस्तार हुआ है। तथापि, निर्यात विभाग के धीमे विकास और फलस्वरूप निर्यात में मद वृद्धि के कारण इस विनिष्ट क्षेत्र में लथवा अन्यान्य क्षेत्रों में निवेश वृद्धि से पूँजी-उत्पादन अनुपात में वृद्धि हुई है, विशेष कर आलोच्य-काल के उत्तरार्द्ध में। और फिर नये क्षेत्रों में हुए निवेश की फल-प्रति में समय लगा है और जहाँ सकल अनुपात पूर्वार्ध के ५३ प्रति शत से उत्तरार्ध में ८७ प्रति शत वार्षिक की तीव्र गति में बढ़ा है, वहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पादन अपेक्षाकृत मद गति से बढ़ा है—उक्त काल में वह २६ प्रति शत से बढ़ कर ३१ प्रति शत ही हुआ। अतएव, यह स्वाभाविक ही है कि दीर्घ-कालीन दृष्टि-कोण से रसद के मामले में विकास अपर्याप्त रहा है।

२

घरेलू वास्तविक स्रोत

घरेलू पूँजी निर्माण की बहुविध आवश्यकताएँ पूर्ण

करने हेतु निवेश के परिमाण में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ वास्तविक साधन-स्रोतों में भी वृद्धि हुई है और कभी-कभी तो निवेश के परिमाण में वृद्धि को सहायता भी मिली है। यह बात दो तरह से हुई। कुछ मूल उद्योगों—उदाहरणार्थ सिमेण्ट—के उत्पादन में इतनी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है कि आयात कम अथवा बिल्कुल बन्द करना पड़ा। दूसरी ओर अचल पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में सहायता देने हेतु लोहे और इस्पात अथवा अन्य बुनियादी वस्तुओं जैसी चन्द सामग्रियों का आयात होने दिया गया। तालिका ५ इस बात का चित्र प्रस्तुत करती है कि घरेलू उत्पादन और/या आयात पर किम हद तक निर्भर रहा गया। यद्यपि लोहे तथा इस्पात और अन्य भवन निर्माण सामग्री (सिमेण्ट को छोड़ कर) का आयात अब भी—विशेष कर उत्तरार्द्ध में—आवश्यक था, तथापि 'निर्माण' के अन्तर्गत सिमेण्ट, लोहे और इस्पात जैसे सामान के घरेलू

तालिका ५

सकल अचल सम्पत्ति निर्माण के प्रातिशत्य स्वरूप निर्माण सामग्री तथा यंत्रों व उपकरणों का घरेलू उत्पादन और आयात (प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

मद	१९४८-४९ में १९६०-६१		१९४८-४९ से १९५४-५५		१९५४-५५ से १९६०-६१	
	उत्पादन	आयात	उत्पादन	आयात	उत्पादन	आयात
१ निर्माण सामग्री इसमें	१०५	२७	२०४	१९	१९२	३०
सिमेण्ट	३२	०१	२७		३५	.
लोहा और इस्पात	५.९	१५	५२	०५	६३	२०
अन्य भवन निर्माण सामग्री	१०४	११	१२५	१४	९४	१०
२ यंत्र और उपकरण जिनमें	१३०	१५१	११३	१५१	१३९	१४९
बुनियादी सामान	८१	८२	७२	१०२	८६	७४
अन्य यंत्रादि	४९	६९	४१	४९	५३	७८
३ योग (१ और २)	२२५	१७८	३१७	१७०	३३१	१७९

स्रोत भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

उत्पादन-क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। इसके दूसरी ओर बुनियादी सामग्रियों तथा अन्यान्य प्रकार के यंत्रादि के घरेलू उत्पादन में सुधार हुआ अर्थात् उसमें वृद्धि हुई, तथापि आयात काफी अधिक हुआ, जिसका परिणाम यह निकला कि आलोच्यवधि में सकल अचल निवेश में उनका स्थान १५ प्रति शत था।

इस प्रकार जहाँ अचल पूंजी निर्माण की वृद्धि में निर्माण सामग्री के उत्पादन-विस्तार ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की, वहाँ चूँकि देश में बुनियादी-आधार का अभाव था इसलिए बुनियादी सामान तथा अन्य प्रकार के यंत्रों में वृद्धि आयात के जरिये की गयी। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उत्तरवर्ती सामानों के घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण उन्नति हुई है, चूँकि आलोच्यवधि में वह सकल अचल निवेश का १३ प्रति शत था। वास्तव में सिमेण्ट तथा बुनियादी सामग्री के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि-दर उनके लिए प्राप्त पूर्ति (तालिका ६ देखें) से

बहुत अधिक रही है। यद्यपि लोहा और इस्पात तथा यंत्रों के पुर्जों के सम्बन्ध में वृद्धि दर बहुत अच्छी रही है तथापि, आलोच्य-काल में उक्त दो मदों के आयात में बहुत वृद्धि हुई है। इसके दूसरी ओर सिमेण्ट के आयात में १४ प्रति शत वार्षिक दर से गिरावट आयी है। उत्तरार्द्ध में उत्पादन तथा आयात (सिमेण्ट को छोड़ कर) दोनों क्षेत्रों में ही तीव्र वृद्धि हुई है और आयात के—खास कर लोहा और इस्पात तथा अन्य यंत्रों के पुर्जों आदि का—जरिये जो साधन-स्रोत प्राप्त किये गये वे उनके घरेलू उत्पादन के जरिये जो वृद्धि हुई उससे काफी अधिक थे। सामान्यत आलोच्य काल में जहाँ समग्र निर्माण सामग्री का आयात यंत्रों/उपकरणों की वार्षिक दर से तीव्र दर से बढ़ा वहाँ उत्पादन तथा प्राप्य पूर्ति दोनों ही क्षेत्रों में प्रथम की अपेक्षा द्वितीय मद की गति तीव्र रही।

तालिका ६

प्राप्य पूर्ति, निर्माण सामग्री तथा यंत्रों व उपकरणों के उत्पादन और आयात में वृद्धि/कमी की वार्षिक दर
(प्रातिशत्य प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

मद	१९४८-४९ से १९६०-६१			१९४८-४९ से १९५४-५५			१९५४-५५ से १९६०-६१		
	प्रा.पू.	उ	आ	प्रा.पू.	उ	आ	प्रा.पू.	उ	आ
निर्माण सामग्री									
सिमेण्ट	१७१	१८२	-१४	१८२	२०५	-०३	१६१	१५९	-२५
लोहा और इस्पात	१६५	१५२	४०८	१२५	१२५	१९२	२०६	१७८	६२५
अन्य	५०	५१	७०	२५	२२	९९	७५	८०	४१
योग	९६	९६	१७२	६३	६७	८४	१२९	१२४	२६०
यंत्र तथा अन्य उपकरण									
बुनियादी सामग्री	८६	१२६	५४	४३	८७	१३	१३०	१६५	९४
अन्य यंत्र	१९५	१३५	१७९	७०	६५	७७	३२०	२०५	२८०
योग	१११	१२८	९८	४९	७६	२९	१७३	१७९	१६७
कुल योग	१०३	१०७	१०३	५४	६९	३२	१५३	१४५	१७३

स्रोत भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकीय मण्डल। प्रा.पू.=प्राप्य पूर्ति, उ=उत्पादन, आ=आयात।

जैसी अपेक्षा की जाती है, सकल पूँजी निर्माण और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण कार्यों सम्बन्धी पूँजी निर्माण सामग्री का हिस्सा (क्रमशः ६३.२ और १०.३ प्रति शत) आलोच्यवधि में यत्रो तथा उपकरणों के हिस्से (क्रमशः २७.९ और ४.५ प्रति शत) से अधिक रहा। (इस सम्बन्ध में विस्तृत आकड़े तालिका ७ में दिये गये हैं।) सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण सामग्री और यंत्रो तथा उपकरणों का सापेक्षिक हिस्सा पूर्वार्द्ध व उत्तरार्ध के बीच दो विशिष्ट उपनतियाँ अर्थात् झुकाव प्रदर्शित करता है। जैसा कि तालिका ७ से स्पष्ट है, उक्त मदों का अनुपात पूर्वार्ध में काफी कम था और उत्तरार्ध में पर्याप्त रूप से बढ़ा। सकल पूँजी निर्माण और सकल राष्ट्रीय उत्पादन के समक्ष कुल सकल अचल निवेश के सम्बन्ध में भी यही प्रवृत्ति दृष्टि-गोचर होती है। यद्यपि दोनों ही 'अर्द्धों' में सकल पूँजी निर्माण के प्रति अनुपात सापेक्षिक रूप से करीब ९१ प्रति शत रहा, लेकिन इसी काल में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति यह अनुपात सापेक्षिक तौर पर १२ से बढ़ कर १७ हो गया। इस प्रकार का अप्रत्याशित झुकाव या मोड़ आलोच्य-काल के उत्तरार्ध में निवेश की गतिविधि के क्षेत्र में जो सामान्य वृद्धि हुई उसके कारण हो सकता है।

तालिका ७

सकल पूँजी निर्माण और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 'निर्माण सामग्री' तथा 'यंत्र-उपकरणों' के क्षेत्र में अचल निवेश का सापेक्षिक हिस्सा और वार्षिक वृद्धि-दर का प्रातिशत्य (१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों पर आधारित)

सकल अचल निवेश	वार्षिक वृद्धि दर	सापेक्षिक हिस्सा	
		सकल पूंजी निर्माण	सकल राष्ट्रीय उत्पादन
निर्माण सामग्री			
१९४८-४९ से १९६०-६१	७.२	६३.२	१०.३
१९४८-४९ से १९५४-५५	७.५	६३.०	८.६
१९५४-५५ से १९६०-६१	६.९	६३.७	११.६

सापेक्षिक हिस्सा			
सकल अचल निवेश	वार्षिक वृद्धि दर	सकल पूँजी निर्माण	सकल राष्ट्रीय उत्पादन
यंत्र और उपकरण			
१९४८-४९ से १९६०-६१	६.९	२७.९	४.५
१९४८-४९ से १९५४-५५	०.५	२७.३	३.१
१९५४-५५ से १९६०-६१	१३.२	२७.९	५.१
सकल अचल निवेश			
१९४८-४९ से १९६०-६१	७.०	९१.१	१४.८
१९४८-४९ से १९५४-५५	५.३	९०.३	११.७
१९५४-५५ से १९६०-६१	८.७	९१.६	१६.७

स्रोत भारत सरकार - केन्द्रीय सांख्यिकीय सङ्गठन।

स्थिर मूल्यों के आधार पर इन मदों की वार्षिक वृद्धि दरों में आलोच्य काल के दौरान तीव्र भिन्नता पायी जाती है। जहाँ निर्माण सामग्री में अचल निवेश की वार्षिक दर ७.५ में कम हो कर ६.९ प्रति शत हुई, वहाँ यंत्रों व उपकरणों की वार्षिक दर दोनों 'अर्द्धों' में ०.५ से बढ़ कर १३.२ प्रति शत तक जा पहुँची। पूर्वार्द्ध में जो नगण्य वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण था युद्ध समाप्ति के तुरन्त बादवाले प्रारम्भिक वर्षों में विदेशों में बुनियादी सामग्री की उपलब्धि का अभाव। किसी भी दृष्टि से देश में १९५४-५५ से पहले निवेश कार्यक्रम इतना सघन नहीं हुआ कि उसकी यंत्रों व उपकरणों में अचल निवेश की वार्षिक वृद्धि-दर के लिए गणना की जा सके। उत्तरार्द्ध में निवेश कार्यक्रम ने जोर पकड़ा। उसमें इस विभाग की वार्षिक वृद्धि-दर में तीव्र सुधार हुआ। फलतः दोनों 'अर्द्धों' में कुल अचल निवेश भी ५.३ और ८.७ प्रति शत की वार्षिक-दर से बढ़ा।

समग्र रूप से देखने पर आलोच्य काल में निर्माण सामग्री की अपेक्षा यंत्रों तथा उपकरणों का विस्तार सापेक्षिक रूप से कम हुआ है। वस्तुतः सकल अचल निवेश में सभी प्रकार के प्रमुख विस्तार में आयातित सामग्री से सहायता मिली है। विशेष कर उत्तरार्ध

के दौरान निवेश के आयात तत्व में तीव्र वृद्धि दृष्टि-गोचर हुई। यद्यपि उनके साथ लोहे तथा इस्पात का उत्पादन काफी बढ़ा तथापि उम सामग्री का आयात भी पूर्वाह्न की अपेक्षा उत्तरार्द्ध में बहुत अधिक था। इस प्रकार सकल अचल निवेश के विस्तार में घरेलू उत्पादन वृद्धि (जिसमें आयात कम या बन्द हुआ, जैसे सिमेंट के मामले में) तथा अधिक आगत (लोहे और इस्पात तथा बुनियादी सामान के मामलों में) दोनों में ही सहायता मिली है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस आयातित सामान की वृद्धि में सहायक होने के नाते हमारी आयात करने की क्षमता पर्याप्त रही है अथवा नहीं।

३

अप्रैल १९४८ के प्रारम्भ में देश के विदेशी विनि-मय सम्बन्धी स्रोत १६ अरब १२ करोड़ रुपये के बराबर थे जो अप्रैल १९५४ के आरम्भ में कम हो कर ९ अरब १० करोड़ रुपये और अप्रैल १९६० के शुरू में ३ अरब ६३ करोड़ रुपये के बराबर रह गये। यद्यपि व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और विशद सेवाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा के कारण उत्तरार्ध में आयात करने की क्षमता में कुछ सुधार हुआ, तो भी अचल निवेश के आयात-तत्व के लिए वित्तीय व्यवस्था करने हेतु विदेशी विनिमय प्रारक्षण का सहारा लेना पड़ा। पूर्वाह्न और उत्तरार्द्ध के मध्य-जैसा कि तालिका ८ से

तालिका ८

वास्तविक आयात और आयात क्षमता की वस्तु-सूचियों और वार्षिक-दरों की वृद्धि/कमी
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्या पर आधारित, आधार १९४८-४९ में १९५८-५५ = १००)

मद	१९४८-४९ से १९६०-६१		१९४८-४९ से १९५४-५५		१९५४-५५ से १९६०-६१	
	वस्तु सूचियाँ	वार्षिक दर	वस्तु सूचियाँ	वार्षिक दर	वस्तु सूचियाँ	वार्षिक दर
वास्तविक व्यावसायिक						
आयात †	१२५३	९८	१०००	७५	१४६९	१२१
निम्न मर्चों से प्राप्त आयात क्षमता						
निर्यात और विशुद्ध सेवाएँ*	१०५५	६१	१०००	१०८	११६१	१४
योग सरकारी ऋण व						
अनुदान	११६६	८२	१०००	९१	१३११	७३
योग अन्य दीर्घ-कालीन पूँजी	१२१६	८०	१०००	६६	१४०२	९४
विदेशी मुद्रा प्रारक्षण	८१९	८२	१०००	४९	६४८	११६

† प्रतिरक्षा सामग्री व स्थापन की खरीद के लिए १९४८-४९ में दरभण्ड को चुकाये गये ७१ करोड़ ९० लाख रुपये के असाधारण भुगतान को छोड़ कर।

* उबार पट्टे (लेण्ड-लीज) के सम्बन्ध में १९५७-५८ में संयुक्त राज्य अमेरिका को भुगतान स्वरूप भेजी गयी ७४ करोड़ ४० लाख रुपये की चाली को छोड़ कर। 'विशुद्ध सेवाओं' में सरकारी अनुदान नहीं है, पर 'निजी' अनुदान शामिल है।

स्रोत रिजर्व बैंक आफ इंडिया।

प्रकट है—व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात व सेवाओं के कारण आयात क्षमता १६१ प्रति शत बढ़ी जो सरकारी ऋण व अनुदान को मिला कर ३११ प्रति शत तक बढ़ी। दीर्घ-कालीन पूँजी को साथ मिला कर देखने से पता चलता है कि यह वृद्धि ४०२ प्रति शत थी। आलोच्यावधि में सरकारी ऋण व अनुदान तथा अन्य दीर्घ-कालीन पूँजी जो कुल विदेशी मुद्रा मिली उसके २३७ प्रति शत थे, यद्यपि पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध के बीच अन्तर बहुत अधिक था—पूर्वाद्ध में उनका प्रातिशत्य ११९ और उत्तराद्ध में ३०८ था। तथापि, इसी काल में वास्तविक व्यापारिक वस्तुओं के आयात में ४६९ प्रति शत वृद्धि हुई। आयात क्षमता से अधिक इस आयात की वित्तीय व्यवस्था वस्तुतः विदेशी मुद्रा प्रारक्षण से की गयी। पूर्वाद्ध की तुलना में उत्तराद्ध में मुद्रा प्रारक्षण के 'बराबर' का आयात काफी कम करके ३५२ प्रति शत कर दिया गया। जबकि व्यापारिक वस्तुओं के आयात में आयात करने की क्षमता की वृद्धि-दर (८ प्रति शत) से अधिक दर (९८ प्रति शत) पर वृद्धि हुई, इसलिए शेष कमी-

पूर्ति के लिए एक ही विकल्प था कि विदेशी मुद्रा प्रारक्षण का सहारा लेना पड़ा। विशेष कर उत्तराद्ध में वास्तविक आयात कुल आयात क्षमता व दर (९४ प्रति शत) से भी काफी ऊँची दर (१२१ प्रति शत) से बढ़े, जिसका परिणाम यह निकला कि विदेशी मुद्रा प्रारक्षण ११६ प्रति शत वार्षिक दर से कम हो गये। इस प्रकार घरेलू अचल निवेश के लिए वास्तविक आयात को परिपूर्णतः कुल आयात क्षमता पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ा।

बुनियादी सामग्री और यन्त्रों के हिस्सों के आयात के फलस्वरूप सकल अचल निवेश के कारण स्वयम् आयात की जानेवाली वस्तुओं की सूची में ही कुछ तब्दीली करनी पड़ी। दोनों 'अर्द्धों' में, जैसा कि तालिका ९ में प्रस्तुत आकड़ों से पता चलता है कि बुनियादी सामग्री के आयात में २५ से ३८ प्रति शत तक वृद्धि हुई, जबकि इसी काल में कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री का प्रातिशत्य क्रमशः ३० और २४ प्रति शत से गिर कर प्रत्येक का २० प्रति शत हो गया। इसके पीछे मुख्य कारण था आयात पर कठोर पाबंदियों

तालिका ९

कुल आयात के प्रातिशत्य स्वरूप बुनियादी सामग्री, कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री का आयात
(प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

अवधि	कुल आयात	बुनियादी सामग्री‡	कच्चा माल	उपभोक्ता सामग्री	
				खाद्य	कुल
१९४८-४९ से १९५०-५१	१०००	२५८	२९८	१६५	२३८
१९५०-५१ से १९५२-५३	१०००	२२६	३११	२०२	२६९
१९५२-५३ से १९५४-५५	१०००	२७१	२८९	१४६	२२५
१९५४-५५ से १९५६-५७	१०००	३५७	२३१	४०	१३२
१९५६-५७ से १९५८-५९	१०००	४०४	१८२	८८	१८६
१९५८-५९ से १९६०-६१	१०००	३८५	१८६	१७६	२६४
१९४८-४९ से १९६०-६१	१०००	३२५	२४२	१३७	२२०
१९४८-४९ से १९५४-५५	१०००	२४८	२९९	१७१	२४४
१९५४-५५ से १९६०-६१	१०००	३८०	२०३	१०६	१९८

‡ बुनियादी सामग्री के लिए वर्ग दिये गये आकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के आकड़ों से कुछ भिन्न हैं।

स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

का लगाया जाना, जिसे १९५७ में उत्पन्न सकट के बाद और भी कठोर कर दिया गया। जहाँ बुनियादी सामग्री के अधिक आयात से अचल पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में सहायता मिली, वहाँ साथ ही साथ कच्चे माल व उपभोक्ता सामग्री के आयात में—कुल आयात के आनुपातिक रूप में—कमी हुई। जहाँ तक देश में औद्योगिक गतिविधि का सम्बन्ध है, कच्चे माल पर पाबन्दियाँ लगा देने से बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई, क्योंकि उससे अर्थ-व्यवस्था और स्वयम् अचल निवेश के विकास में गत्यावरोध आनेवाला था।

यद्यपि जब—तब कम उत्पादन होने के कारण काफी तादाद में खाद्यान्नों का आयात करना आवश्यक हुआ है, तथापि उपभोक्ता सामग्री के आयात पर पाबन्दियाँ लगाना सामान्यतः हमारे आयात व्यापार का एक उपयोगी अंग रहा है। वास्तव में उपभोक्ता सामग्री के कुल आयात में खाद्यान्नों के आयात का अनुपात, समग्र अवधि में ६२ प्रति शत रहा है, लेकिन पूर्वाद्ध में जो ७० प्रति शत था वह उत्तराद्ध में ५४ प्रति शत हो गया। यद्यपि उत्तराद्ध में खाद्यान्नों का उत्पादन २० प्रति शत बढ़ा, अधिक आयात करना न केवल घरेलू उपयोग पूरा करने बल्कि केन्द्रीय प्रारक्षण बनाये रखने के लिए भी करना आवश्यक

हो गया। जैसा कि तालिका १० से प्रकट है, पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध में खाद्यान्नों के घरेलू उपभोग में यद्यपि क्रमशः २५ और २७ प्रति शत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई, लेकिन इसके समक्ष उक्त काल में खाद्यान्नों के उत्पादन में क्रमशः ३७ और ३२ प्रति शत की दर से वृद्धि हुई। उपभोग (मानवीय तथा कुल) में विशुद्ध आयात वास्तव में उत्तराद्ध में कम हुआ और किसी भी दृष्टि से वह बहुत ही कम प्रातिशत्य (३ से ५ प्रति शत तक) के रूप में था। तिस पर भी विशुद्ध आयात जो कि पूर्वाद्ध में ४ प्रति शत वार्षिक दर से कम हुए थे वे उत्तराद्ध में २९ प्रति शत वार्षिक की दर से बढ़े, जो कि कुल उपलब्ध के प्रति खाद्यान्नों के स्टॉक के अनुपात में हुई तीव्र वृद्धि (६ से १६ प्रति शत तक) पर प्रकाश डालते हैं। तथापि, मूल्य की दृष्टि से खाद्यान्नों के आयात और कुल उपभोक्ता सामग्री दोनों में ही उत्तराद्ध में कमी हुई और इससे तथा कच्चे माल के आयात में कमी के कारण कुल आयातित वस्तुओं में बुनियादी सामग्री का अनुपात बढ़ा।

वस्तुतः निजी तथा समग्र उपभोग्य परिव्यय में कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री (खाद्यान्नों सहित) का सापेक्षिक हिस्सा पूर्वाद्ध की तुलना में उन्नत में

तालिका १०

भारत में खाद्यान्नों की स्थिति

वर्ष	वार्षिक वृद्धि (प्रातिशत्य)			उपभोग के प्रातिशत्य		प्राप्त रसद के प्रातिशत्य
	घरेलू उत्पादन	विशुद्ध आयात	कुल उपभोग	स्वरूप मा उ	स्वरूप कुल	
१९४८-४९ से १९६०-६१	३४	१२५	२६	४५	४१	११५
१९४८-४९ से १९५४-५५	३७	३९	२५	५२	४७	६१
१९५४-५५ से १९६०-६१	३२	२८९	२७	३४	३१	१६०

मा उ = मानवीय उपभोग।

टिप्पणी आकड़े मौलिक रूप से हजार टनो में हैं और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के 'पेपर' से लिए गये हैं।

काफी कम कर दिया गया, जैसा कि तालिका ११ से प्रकट है। हाँ, तालिका ११ में दिये गये आकड़े अस्थायी हैं और उनमें सेवाओं पर हुआ खर्च भी शामिल है। मात्र सामग्री यानी अकेले माल पर ही कितना खर्च हुआ उसे अलग करके देखना सम्भव नहीं बन पड़ा है। तथापि, मोटे तौर पर जो झुकाव परिलक्षित है उनमें निश्चय ही यह सकेत मिलता है कि इनके अनुपात

थी, तथापि विजली सम्बन्धी सामान के सम्बन्ध में प्रायः उदारता बरती गयी। उत्तरार्द्ध में इनके आयात में वृद्धि हुई। इसके विपरीत इसी अवधि में (जैसा कि तालिका ११ में प्रस्तुत आकड़ों से द्रष्टव्य है) उपभोग परिव्यय के प्रति कच्चे माल के आयातानुपातों में तीव्र कमी आयी है। बाजार की मुक्तावस्था की अपेक्षा आयात नियंत्रण और 'कोटा' निर्धारण का अपेक्षाकृत

तालिका ११

घरेलू उपभोग परिव्यय के प्रातिशत्य स्वरूप कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री का आयात
(प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

आयातित वस्तुएँ	१९४८-४९ से १९६०-६१		१९४८-४९ से १९५४-५५		१९५४-५५ से १९६०-६१	
	निजी	कुल	निजी	कुल	निजी	कुल
कच्चा माल	२०.५	१९.०	२३.४	२१.९	१८.१	१६.६
उपभोक्ता सामग्री	१८.६	१७.३	१९.१	१७.९	१७.६	१६.२
इसमें						
खाद्यान्न	११.५	१०.७	१३.४	१२.६	९.५	८.७
कुल	३९.१	३६.३	४२.५	३९.८	३५.७	३२.८

टिप्पणी घरेलू उपभोग व्यय में सामान व सेवाओं के अंक भी शामिल हैं। कुल उपभोग्य खर्च में निजी तथा सरकारी खर्च—प्रचलित मूल्यों पर आधारित—शामिल है। इन अंकों के सकलन में कई जगह समजन किया गया है। चूँकि विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निमित्त करते हुए खर्च—एक्सपेण्डीचर जेनरेटिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट (केन्द्रीय सांख्यिकीय मण्डल राष्ट्रीय आय का अनुमान)—दिखानेवाले विवरण में निजी वर्तमान खर्च के अंक निजी विशुद्ध पूँजी निर्माण के अंकों के साथ मिला दिये गये हैं, इसलिए १९४८-४९ से १९५४-५५ तक के प्रत्येक वर्ष के लिए कुल सकल पूँजी निर्माण के प्रति निजी पूँजी निर्माण के अनुपातों का प्रचलित मूल्यों के आधार पर (के सा स के 'पेपर' में उपलब्ध) विशुद्ध पूँजी निर्माण पर प्रयोग किया गया है। प्रचलित मूल्यों के आधार पर सामग्री और सेवाओं पर निजी वर्तमान खर्च के अंक प्राप्त करने के लिए मिले हुए आकड़ों में से उक्त प्रकार से प्राप्त आकड़े निकाल लिये गये हैं।

सन् १९५५-५६ से १९६०-६१ तक के वर्षों के लिए निजी उपभोक्ता खर्च के आकड़ों के सा स के 'पेपर' में उपलब्ध आकड़ों को पुनः व्यवस्थित करके सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आकड़ों से प्राप्त किये गये हैं। कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री के आकड़े 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' से प्राप्त किये गये हैं।

में कमी हुई है। यह कमी उपभोक्ता सामग्री की अपेक्षा कच्चे माल के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक हुई है।

उत्तरार्द्ध में निजी तथा कुल उपभोक्ता खर्च के प्रति खाद्यान्नो के आयात के अनुपातों में तीव्र कमी होते हुए भी कुल उपभोक्ता सामग्री के आयातानुपातों में तनिक-सी कमी ही आयी। यद्यपि इस विशिष्ट श्रेणी में आने-वाली वस्तुओं के आयात पर सर्वाधिक कठोर पाबन्दियों

इस पर अधिक प्रभाव पड़ा है। निस्संदेह पूर्वार्द्ध की अपेक्षा उत्तरार्द्ध के दौरान कृषि तथा औद्योगिक, दोनों ही प्रकार के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन का औसत सूचकांक (आधार १९४९-५०=१००) १९४९-५० से १९५४-५५ (वर्ष का अन्त जून माह में) के १०४३ से बढ़ कर १९५४-५५ से १९६०-६१ में १२५१ हुआ है, जिसमें करीब

२० प्रति शत ऊर्ध्वोन्मुखी उपनि दृष्टिगोचर होती है। औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक औसत सूचकांक (आधार १९५१=१००) भी ३७४ प्रति शत बढ़ा है—पूर्वाद्धि में वह १०३३ या जोर उत्तरार्द्ध में बढ़ कर १४१९ हो गया। इस प्रकार की इस उन्नति का घरेलू उपभोक्ता परिव्यय के प्रति कच्चे माल का आयातानुपात कम करने में प्रभाव पड़ना चाहिए। इतना होने पर भी कुछ उद्योग न केवल अपने गयत्रों को उनकी अनुकूलतम क्षमता पर चलाने लगे जिस क्षमता का लाइसेंस मिला हुआ था उगले अन्तर रहते हुए उत्पादन को अधिकतम बनाने के लिए भी बिल्कुल आयातित कच्चे माल पर ही निर्भर थे।

बुनियादी सामग्री, कच्चे माल और खाद्यान्न हमारे आयात व्यापार में तीन मुख्य प्रतिसर्पिणी रहे हैं तथा सामान्यतः बुनियादी सामग्री के आयात के साथ या तो कच्चे माल के आयात में कमी हुई है या खाद्यान्न के आयात में अथवा फिर दोनों के आयात में। जैसा कि पीछे तालिका ९ के अंकों में प्रकट होता है कि बुनियादी सामग्री का आयात सामान्यतः विलोमरूप से कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री (विशेषकर खाद्यान्न) से भिन्न रहा है। कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री के सापेक्षिक हिस्से में कमी के साथ बुनियादी सामग्री के हिस्से में वृद्धि हुई है। इस प्रकार जहाँ तक बुनियादी सामग्री के आयात ने अचल निवेश का स्तर निर्धारित किया है, अचल निवेश को अन्ततोगत्वा खाद्यान्न और/अथवा कच्चे माल की कमी ने प्रतिबद्ध कर दिया है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी और अन्ततोगत्वा परमावश्यक कच्चे माल तथा उपभोक्ता सामग्री के आयात को बन्द कर देना एक असंभव बात बना देना मुख्य बाधा रही है।

आयात क्षमता जब निजी या कुल उपभोग खर्च से अधिक ऊँची वार्षिक-दर से बढ़ी तो नकल अचल निवेश की वृद्धि में सहूलियत हुई (देखिए तालिका १२)। इसके ऊपर उत्तरार्द्ध में अधिक जोर दिया गया, यद्यपि यह बात नहीं है कि पूर्वाद्धि में

उम पाँच जोर न दिया गया हो। यद्यपि वास्तविक आयात आयात क्षमता की दर की अपेक्षा तीव्र दर से बढ़े, तो भी युद्ध समाप्ति पर जो पीण्ड-पावना भारी नादाव में उपलब्ध था उसमें उनकी वित्तीय व्यवस्था में जो अन्तर था वह काफी समय तक पूरा किया जाता रहा। उस प्रकार आयात क्षमता में वृद्धि और उसके साथ घरेलू उपभोग की वस्तुओं के आयात में कमी में देश कुल आयात में बुनियादी सामग्री का हिस्सा बढ़ाने तथा सकल अचल निवेश को बढ़ावा देने में समर्थ हो सका। इसलिए यह स्वाभाविक था कि सकल अचल निवेश में आयात क्षमता के साथ प्रत्यक्ष रूप में प्रतिबन्धन आया, यद्यपि अनुवर्ती की वार्षिक वृद्धि दर पूर्ववर्ती में बहुत तीव्र थी। इस विस्मयजनक स्थिति का कारण यह हो सकता है कि विदेशों से प्राप्त सरकारी ऋण व अनुदान की बड़ी-बड़ी रकम अनपेक्षित पड़ी रही, जोकि या तो आवश्यक परिमाण में या फिर निरूपित समय के अन्दर-अन्दर खर्च नहीं की जा सकी। इसके अनिश्चित अनुदानों का काफी हिस्सा सरकारी हिस्से में खाद्यान्न का आयात करने के लिए था और सम्भवतः देश में अचल निवेश के विकासार्थ नहीं था।

उपभोग के रूप में यह कहा जा सकता है कि युद्धोत्तर-काल में पंजी संचयन में विकास की गति उल्लेखनीय रही है, जिसकी प्राप्ति मुख्यतः सरकारी अभियोग के जरिये अचल विनियोजन यानी निवेश में वृद्धि के कारण हुई। अचल पूँजी निर्माण के क्षेत्र में निजी विभाग ने भी प्रशंसनीय भूमिका अदा की है। यद्यपि नन्द दिशाओं में घरेलू उत्पादन से सहायता नहीं है तथापि अचल निवेश की आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन-स्रोत प्राप्ति का मुख्य जरिया आयात व्यापार रहा है। इसमें किसी हद तक वृद्धि-पात आयात क्षमता से सहायता मिली है, जोकि घरेलू उपभोग परिग्रह की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ी है। निसर्ग भी, वास्तविक आयात, आयात क्षमता से भी तीव्र गति से बढ़ा है, जिस कारण विदेशी

मुद्रा प्रारक्षण का सहारा लेना आवश्यक हो गया। वर्षों के दौरान प्रारक्षणों में तीव्र कमी आने से परिपूर्ण अचल निवेश की प्रगति रोकने में बुनियादी सामग्री का आयात मुख्य पहलू रहा है, जोकि आयात व्यापार में कच्चे माल व खाद्यान्नों के सापेक्षिक महत्व पर निर्भर रहा है। यद्यपि कृषि तथा उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है, पर दबाव पड़ता है, और अनुदान स्पष्टतः चिरकाल

तालिका १२

सकल अचल निवेश, वास्तविक आयात, आयात क्षमता और घरेलू उपभोग परिरक्ष्य की वार्षिक वृद्धि-दर का अनुपात
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर)

अवधि	सकल अचल पूँजी	वास्तविक आयात	आयात क्षमता	घरेलू उपभोक्ता व्यय*		
				निजी	सरकारी	कुल
१९४८-४९ से १९६०-६१	७०	९८	८०	२५	४.५	२.६
१९४८-४९ से १९५४-५५	५३	७.५	६६	२२	२६	२२
१९५४-५५ से १९६०-६१	८७	१२१	९४	२७	६३	३०

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तथा एशिया और उद्गूर पूर्व का आर्थिक सर्वेक्षण, १९६१।

टिप्पणी : * स्थिर मूल्यों के आधार पर निजी और सरकारी वर्तमान व्यय प्राप्त करने के लिए तालिका ११ की टिप्पणी में दिये गये तरीके के अनुसार प्राप्त प्रचलित मूल्यों के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति सामग्री और सेवाओं पर निजी तथा सरकारी वर्तमान व्यय का जो अनुपात है उसका १९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर प्रयोग किया गया। आकड़े आवश्यक रूप से ही अस्थायी हैं और सदैव की भाँति मरने-मामान तथा सेवाओं के आकड़े भी इनमें शामिल हैं। दोनों को अलग-अलग करना सम्भव नहीं जान पड़ा है। आशा है मामूली त्रुटि रहते हुए भी मोटे तौर पर जिधर झुकाव है, वह द्रष्टव्य है।

तथापि सामान्यतः उपभोक्ता सामग्री और विशेष कर खाद्यान्नों का आयात रोक रखना मुश्किल रहा है। कच्चे माल के आयात पर लगी पाबन्धियाँ अर्थ-व्यवस्था के चन्द क्षेत्रों की गति मद करने के कारण रही हैं। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था की बुनियादी स्वरूपात्मक कुव्यवस्था अब भी गेप है—आर्थिक विकास की समग्ररूपेण आवश्यकताओं के प्रति अन्वोन्याश्रय रूप से साधन-स्रोतों की पूर्ति में कमी अब भी बनी हुई ही है।

दीर्घ काल तक आयात क्षमता में अधिक आयात करने के कारण उत्पन्न कमी की वित्तीय व्यवस्था विदेशी मुद्रा प्रारक्षणों से की जा सकी। पिछले चन्द

के लिए जारी नहीं रह सकते। इन सबसे एक ही दिशा का निदर्शन होता है कि निर्यात-आय को अधिकतम बनाया जाय। उपसे ही देश में अचल पूँजी निर्माण की प्रक्रिया को गति मिल सकती है। निस्संदेह शचर निवेश की दर तीव्र बनाने से चतुर्दिक कठिनाइयाँ व कष्ट आयेगे, किन्तु ये सब शांति, धैर्य और पौष्टिक के साथ सभी को सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि पूँजी संचयन की समस्या न तो अस्थायी ही है और न उस लिहाज से कोई प्रासंगिक विषय ही।

आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामोद्योग

बहराम होरमसजी मेहता

आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर और ग्रामोद्योगों के विकासार्थ दृष्टिकोण को सम्पूर्ण रूप में उन क्षेत्रों की आर्थिक विकास की समस्याओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण से अलग नहीं किया जा सकता है। आदिवासी प्राकृतिक स्रोतों तथा कौशल में सम्पन्न हैं तथा उनमें सादर्य-भाव भी है। अतः आदिवासी क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को प्रगति मार्ग पर उन्मुख करने के लिए आवश्यक यह है कि स्थानीय जनसमूह को उचित प्रशिक्षण दिया जाय तथा प्राकृतिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग किया जाय।

सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास की दिशा, प्रकृति-किस्म तथा गति एक ही नहीं हो सकती है, किन्तु जहाँ कहीं भी नेतृत्व, शैक्षणिक प्रगति तथा उन्नत आवागमन प्राप्य हों, प्रगति की गति तेज हो सकती है। जहाँ भी ये तीन साधन अनुपस्थित हैं अथवा सीमित रूप में उपस्थित हैं, वहाँ प्रगति अत्यंत मन्द तथा यहाँ तक कि नगण्य होगी। भारत के वन्य प्रदेशों में जहाँ कि मुख्यतः आदिवासी निवास करते हैं तथा जिनकी संख्या ३ करोड़ से अधिक है, विकास का नया दृष्टिकोण कार्यरत है। दुर्भाग्यवश विकास संस्थाओं के पास ऐसे क्षेत्रों के प्राकृतिक साधनों तथा निवासियों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी तथा ज्ञान नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की सामान्य पद्धति सहज ही प्रारंभ नहीं की जा सकती है और यद्यपि हाल ही में बहुमुखी योजना-क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत हुई है, किन्तु वे जटिल समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं जो कि वन्य अर्थ-व्यवस्था के सघन विकास के लिए अत्यावश्यक हैं।

घाटी-क्षेत्र-सिद्धान्त

आदिवासी क्षेत्र में कुटीर तथा ग्रामोद्योग के विकासार्थ दृष्टिकोण को सम्पूर्ण रूप में उस क्षेत्र की आर्थिक विकास की समस्याओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त,

आदिवासी क्षेत्र के आर्थिक विकास की समस्या इन अद्वितीय विकसित तथा कम जनसंख्यावाले क्षेत्रों की भूमि-समस्या की प्रकृति उन क्षेत्रों में प्रचलित कृषि प्रणाली तथा मानव शक्ति की स्थिति में बहुत अधिक सम्बन्धित है। सर्वप्रथम, वन्य अर्थ-व्यवस्था के अध्ययन तथा ग्रामीण एवम् वन्य अर्थ-व्यवस्था की महत्वपूर्ण भिन्नताओं को जानने के लिए सघन प्रयास करना आवश्यक है। घाटी-क्षेत्र-सिद्धान्त इन भिन्नताओं की अच्छी व्याख्या करता है, जिसके अनुसार प्राकृतिक खंडों को व्यापक तौर पर ६ प्रमुख किस्मों में विभाजित कर सकते हैं (१) पर्वतीय तथा वन्य क्षेत्र, (२) सामान्य घास-क्षेत्र तथा प्रमुख घास-क्षेत्र, (३) भिन्न भू-तत्व तथा सिंचाई की सुविधाओंवाले मैदान, (४) उर्वर मिट्टी तथा सिंचाई-सुविधाओं से युक्त उपवन-भूमि तथा नदी की घाटियाँ, (५) वाणिज्य का अवसर प्रदान करनेवाले समुद्र-तट तथा तटीय प्रदेश, और (६) कठिन अवरोधों से युक्त महस्थल। ग्रामोद्योग के विकास कार्यक्रम बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे यदि योजनाएँ क्षेत्र के पाषाण तथा प्राकृतिक साधनों और जनता तथा उसकी अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालनेवाली मुख्य विशेषताओं के अध्ययन पर आधारित हों।

आदिवासी क्षेत्र सतत पर्वतीय तथा वन्य क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं और कभी-कभी विघेपकर पर्वत-शृंखलाओं के गिरिपादों के समीप घास के बड़े मैदान भी इसमें आ

जाते हैं। सामान्य मैदानी क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों में अधिक अच्छे तथा भिन्न प्राकृतिक साधन होते हैं।

ऐतिहासिक रूप में आदिवासी क्षेत्रों में आखेटक रहते थे, जिन्होंने उन्नतिशील अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया। वे पशु जगत की अमूल्य उपयोगिता से अच्छी तरह अवगत थे। अब भी वन्य पशु स्थानीय तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में योगदान कर सकते हैं। वे देश की भोजन-आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं और पशु चर्म औद्योगिक कार्यों तथा निर्यात के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

कच्चे माल

हाल ही में सनपुड़ा पहाड़ियों पर गोडवाना केन्द्र अस्तित्व में आया है। वह विशेष प्रकार के फूल उगाने तथा औषधियों और विदेशी पौधे लगाने की सम्भावनाओं की खोज कर रहा है। तेल युक्त घासों से बड़ी सम्पत्ति का उत्पादन हो सकता है। सावधानीपूर्वक संगठित तथा व्यापक वानस्पतिक सर्वेक्षण से हमारे वन्य क्षेत्रों के प्रचुर पौधों के उपयोग की जानकारी हो सकती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मिट्टी मिलती है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। मिट्टी-बर्तन-निर्माण के लिए ये मिट्टी अत्यंत मूल्यावान हैं। औद्योगिक कार्यों में दुर्लभ मिट्टी प्रयुक्त होती है तथा कुछ मिट्टी स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी है। जब तक इन अनुपयोगी प्रतीत होने वाले आर्थिक साधनों की उचित खोज तथा उनका अध्ययन नहीं होता, आदिवासी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति नहीं कर सकती।

प्रस्तर, काष्ठ तथा चिक्कण मृत्तिका ही ऐसे कच्चे माल रहे हैं जिनको आदिवासियों ने शताब्दियों से उपयोग किया है। जहाँ पत्थर पाये जाते हैं उससे दूर मैदान निवासी पत्थर का प्रयोग करते हैं, किन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में कदाचित् ही प्रस्तर खाने विकसित हुई है, शायद इसका कारण परिवहन तथा आवागमन की सुविधाओं का अभाव रहा हो। यद्यपि आदिवासी क्षेत्रों में अपरिमित प्रस्तर साधन उपलब्ध हैं, किन्तु

उनका उपयोग किये बिना ही उन क्षेत्रों में प्रति मील २०० रुपये की लागत की सड़के बनायी गयी हैं।

वाणिज्य उपयोगी काष्ठ उत्पन्न करनेवाले वृक्षों, अथवा वन्य फलों अथवा शोभावृक्षों का उपयोग शायद ही आर्थिक विकास का योजनाबद्ध कार्यक्रम हो। महुआ, अचार, बेर, चिरौजी, वन्य आम, जामुन आदि जैसे वृक्ष, जो समृद्धि तथा अभाव के दशकों में लोगों के लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुए हैं, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग के आयोजकों का उपयुक्त ध्यान नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

आदिवासी अर्थ-व्यवस्था का विकास

कुटीर उद्योगों के आयोजक गहरी ममाज के औद्योगिक विकास की विशाल आयोजनों के समक्ष किसी प्रकार की हीन ग्रन्थि में पीड़ित प्रतीत होते हैं। साधारणतः लोगों का यह विश्वास है कि कुटीर उद्योग अवश्य ही लघु होने चाहिए और प्रबन्ध तथा संगठन की क्षमताओं के कारण ही उनके विकास की योजनाएं असफल होती हैं। क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल की विशाल मात्रा का उपयोग करना लाभदायक है। जन-शक्ति समस्या, स्थानीय कौशल तथा बाज़ार का गम्भीर अध्ययन अवश्य करना चाहिए, और तब समस्त स्थानीय सामग्रियों को स्थानीय आदिवासी अर्थ व्यवस्था के विकास में योगदान देना चाहिए। सिर्फ औद्योगिक उपयोगितावाले कच्चे मालों को प्रमुख शहरों तथा विदेशों में उचित तौर पर बेचना चाहिए।

शताब्दियों की उपेक्षा तथा उर्वरको एवम् अन्य रसायन-उपयोग की अनुपस्थिति के कारण सौ वर्षों में भी अधिक पुराने वृक्ष ऐसे फल प्रदान कर रहे हैं जिनकी बिक्री बहुत मुश्किल है। पर्वतों तथा वन्य क्षेत्रों में पादपजात के पुनर्स्थापन में आदिवासियों को बड़ी सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है।

एक आदिवासी क्षेत्र में औद्योगिक विकास चार प्रमुख बातों पर ही आधारित होना चाहिए (अ) कच्चे माल की उपलब्धि, (आ) उत्पादक समुदाय में उपभोक्ता की आवश्यकता, (इ) स्थानीय बाज़ार की आवश्यकताएँ और (ई) अतिरिक्त श्रम तथा लोगों

को अवकाश-समय की उपलब्धि। कच्चे माल पाव्य है, किन्तु उनका उपयोग थोड़े से विक्रय-योग्य वस्तुओं के उत्पादन में ही होता है। आदिवासी केवल स्थानीय साप्ताहिक बाजार में आगत हैं, और कभी-कभी वे समीप के नगरीय बाजार का भी लाभ उठाते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जे कच्चे मालों की उपलब्धि, उनके संभव उपयोग तथा उक्त क्षेत्र के बाहर के प्राकृतिक साधनों में अनभिज्ञ है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकासार्थ प्रकृति-प्रदानों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उनमें पहल, व्यापारिक क्षमता एवम् उत्पादन के तौर-तरीके के ज्ञान की कमी है।

उनका घरेलू जीवन सामान्य गाँवों तथा प्रायः आत्मनिर्भर है। प्रकृति की गोद में रहने तथा जीवन-स्तर की कोई चिन्ता नहीं रहने के कारण वे मनुष्य-जात में जैसा प्रतीत होते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास सम्बन्धी उनकी आवश्यकताएँ तथा जीवन-सुख के लिए जोड़े-पहुँच विलास की प्राप्ति के कारण अब तक ग्रामीणों के विकास में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है। परिवर्तन-योजना क्षेत्र में, जहाँ कि मध्य प्रदेश के गोडवाना केन्द्र ने गोड लोगों में काम करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त किया है, पाँच सौ वर्गमील के क्षेत्र में गाँवों की एक दर्जन बड़ई, राजगीर, लोहार, कुम्हार तथा टोकरी बनाने वाले मिले।

बाजार का अभाव

संस्कृति-सगर, मूल्य-वृद्धि, तथा पारिवारिक और नौकरियों में अभिवृद्धि होने के फलस्वरूप गन्द परन्तु निरन्तर सुधार हो रहा है। परन्तु सामुदायिक योजना अधिकारीगण कुछ निम्न कोटि का प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त कारीगरों को संगठित करने अथवा समीपवर्ती नगरों में बाजार की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में वर्तमान बाजारें मौसमी, अस्थायी तथा अव्यवस्थित हैं। वे लोगों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए लगायी जाती हैं, किन्तु दूग्गनदार तथा छोटे व्यापारी औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद बड़े बाजारों

में पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। संगठित बाजारों तथा परिवर्तन के समुचित सरल तथा सस्ते साधन के अभाव और स्थानीय उत्पादनों के विक्रयार्थ गैर-आदिवासियों पर उनकी लगभग पूर्ण निर्भरता के कारण अब तक आदिवासी क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं हो सका है।

आदिवासी क्षेत्रों में मानव शक्ति की समस्या बड़ी उत्पन्नपूर्ण है। सम्पूर्णरूपेण जनसंख्या कम है, ग्राम समुदाय भी बहुत छोटा है तथा खेत भी बहुत छोटे हैं। वस्त्र तथा सामुदायिक विकास के अधिकारीगण अनियमित रूप से काम करते हैं, इसलिये लॉग ग्रामोद्योगों का काम स्थायी तौर पर करने में असमर्थ हैं।

प्रतिकूल जलवायु

आदिवासी क्षेत्रों में मित्रिया पुरुषों में अधिक काम करती हैं। पुरुष दूर-दूर के स्थानों को जाने में अधिक समय बिताते हैं और उसे स्थायी रूप से कोई काम करने अथवा समय पर काम करने की आदत नहीं है। उसमें काम करने की इच्छा का अभाव होता है। जलवायु के कारणों में वह साल भर नियमित रूप से काम नहीं कर सकता है। वरसात के दिनों में ६० प्रतिशत से भी अधिक पुरवे अलग पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि समीपवर्ती गाँवों से भी आवागमन बन्द हो जाता है। पुतार् तथा फसल कटाई के समय मजदूरों की कमी रहती है। जाड़े के दिन, जबकि अधिक काम हो सकता है, ठंडे और छोटे होते हैं और इसलिए पर्याप्त अवकाश नहीं मिलता है। मुख्यतः गर्मी में, मार्च से मई के अन्त तक अवकाश मिलता है और वह होली का समय होता है जबकि कई दिनों तक उत्सव तथा नृत्य होते हैं और उसके बाद ही नारी, तीर्थयात्रा तथा अनेक उत्सवों का समय आता है। तदनन्तर ऐसे दिन आते हैं जो वरसात से बचने के लिए घर की छतों तथा दीवारों को सुधारने में लग जाते हैं। और फिर, खेत बुवाई के लिए तैयार किये जाते हैं।

आदिवासियों ने अनेक शिल्पकलाओं में अपने कौशल तथा तकनीकाजी का विकास किया है, जो आधुनिक

ग्रामोद्योगों के लिए आवश्यक कौशल से अलग है। पिछड़ेपन तथा ग्रामोद्योग के अर्द्धविकास के मुख्य कारणों में से एक है—ऐसे नेतृत्व का अभाव, जिसमें वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्राप्त कौशल को उचित दिशा में पलटने तथा नवीन कौशल को विकसित करने का ज्ञान हो।

सामुदायिक विकास अधिकारियों द्वारा आयोजित अधिकांश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उचित ढंग से नहीं तैयार किये जाते हैं और उन कार्यक्रमों का संचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा नहीं होता है जो स्वयं औद्योगिक युग के लिए आवश्यक नव-कौशल तथा गति से युक्त हो। प्रयुक्त औजार तथा साधन निम्न कोटि के हैं। प्रशिक्षण काल बहुत सीमित है और अच्छी कारीगरी तथा उच्च श्रेणी के वस्तु-निर्माण के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है। आर्थिक व्यवस्था को पुराने से नये में शीघ्र बदलने के लिए बिल्कुल नये विचारों की आवश्यकता है।

वैविध्यपूर्ण अर्थ-व्यवस्था

यह समझना आवश्यक है कि आदिवासी अर्थ-व्यवस्था तभी समृद्धिशाली होगी, जबकि वह मिश्रित अर्थ-व्यवस्था हो। वन्य अर्थ-व्यवस्था के विकास में, आखेट के महत्वपूर्ण योगदान के बिना भी, वन सवर्धन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्रों में 'आदिवासी कृषि' तथा पशु-पालन का अपना विशेष स्थान है, और मैदानी कृषि पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी तथा जलवायु के अनुकूल नहीं हो सकती। आदिवासी दस्तकारियाँ, वन सवर्धन, गिरि क्षेत्रीय ज्वार तथा बाजरे की खेती, मुर्गी-पालन, मधुमक्खी-पालन, बागवानी आदि केवल पूरक रूप में ही स्थान पा सकती हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामोद्योग के विकास की समस्या के हल के लिए आवश्यकता है—छोटे परन्तु अनुकृया-शील समुदायों का गहन अध्ययन तथा शोध कार्य एवम उनमें अधिक काल तक धैर्यपूर्ण कार्य। शहरों को सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाएं उच्च पारिश्रमिक की अपेक्षा किये बिना ही प्रदान करनी चाहिए, जो कि असंगठित तथा

तथा पारिश्रमिक न दे सकनेवाली अर्थ-व्यवस्था के लिए संभव नहीं है। आदिवासी कच्चे माल, कौशल और सौन्दर्य भाव रखते हैं, किन्तु शहरों तथा आदिवासी क्षेत्रों के सम्पर्क को अभी भी सघन तथा परस्पर लाभकारी होना बाकी है, जिससे आदिवासी अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त योगदान के लिए ग्रामोद्योगों की उत्पत्ति तथा उसका विकास हो सके।

सुखी जीवन के लिए प्रशिक्षण

सात वर्षों के प्रयास से निर्मित गोडवाना केन्द्र एक प्रयोगात्मक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ विकासशील आदिवासी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गोड जनता में शिक्षा के समग्र कार्यक्रम के विकास का प्रयोग चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है तीन वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उन्नत कृषि तथा बढईगीरी, ईंटे बनाने का काम, सूत की कताई और बुनाई जैसे शिल्पों की कुशलता का विकास हो सके और युवक ऐसी वृत्ति के लिए तैयार हो सके कि वे आदिवासी वातावरण में अपनी अनुकूलनीयता न नष्ट करें। शारीरिक योग्यता, नैतिक शिक्षा तथा पौष्टिक शरीर विकास के लिए प्रशिक्षण, तीन वर्ष के कठोर श्रम से युक्त जीवन का एक अंग है। परन्तु जहाँ शिक्षा-कक्ष, वर्कशाप तथा पुस्तकालय में निरन्तर शारीरिक काम करना पड़ता है, वहाँ जीवन सुखी होता है।

केवल सही शिक्षा द्वारा ही प्रगतिशील तथा जागृत आदिवासी समाज के लिए ऐसी नींव डाली जा सकती है, जिसमें नेतृत्व, पहल तथा संगठित प्रयास की क्षमता हो, और जो सुन्दरतम अवसरों से युक्त तथा पहले से ही आधुनिक जीवन की कला से सम्पन्न लोगों के साथ-साथ आदिवासी समाज में सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति लाने की शक्ति रखती हो। ग्राम-नगर, वन-समतल मैदान, मानसिक-भावनात्मक विकास के स्तर और जीवन-स्तर के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए।

कृषिक अनुसंधान और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था

अब्दुर रहीम खॉ

खेती में सुधार करने के लिए कृषिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राविधिक विकास में सरकार की कितनी रुचि है, यह तो इसी से परिलक्षित है कि देश भर में उसने अनेक अनुसंधान संस्थायें स्थापित की हैं। उक्त संस्थाओं में प्राप्त सफलता का यद्यपि बहुत बड़ा व्यावहारिक मूल्य है, तथापि ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं के कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

यद्यपि खेती भारत का सबसे बड़ा पेशा है तथा उसमें देश की करीब ७० प्रतिशत जनता लगी है और राष्ट्रीय आय में उसका आधे से भी अधिक हिस्सा रहता है, फिर भी वह देश की अनवरत रूप से बढ़ रही आबादी का भरण-पोषण करते रहने में समर्थ नहीं हो पायी है। भारत में औसत प्रति एकड़ उत्पादन और भारतीय कृषक की प्रति व्यक्ति आय सम्भवतः ससार में सबसे कम है। आज भी खेती का काम एक जीवन-मार्ग के रूप में होता है, व्यवसाय के रूप में नहीं। पिछले चन्द वर्षों में प्रविधि के क्षेत्र में महान विकास हुए हैं और एक तरह से उन्होंने क्रान्ति-सीला दी है, किन्तु ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

विज्ञान की देन

कृषि क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में कृषिक अनुसंधान ने जो भूमिका अदा की है, उसका मूल्यांकन करना रुचिकर हो सकता है। पिछली सदी में विज्ञान ने कृषि को तीन महत्वपूर्ण देन दी। प्रथम देन थी १८४३ में उर्वरक उद्योग का प्रादुर्भाव। उर्वरक और मृत्तिका के बीच जो प्रतिक्रिया होती है, उसके आधार पर उर्वरक प्रयोग तथा वर्गीकरण की तकनीक विकसित की गयी। इससे करीब ६० वर्ष बाद बेहतरीन किस्मों के पौधे उत्पादित करने का मार्ग ढूँढ़ निकाला गया और, कृषि के लिए यांत्रिक शक्ति का उपयोग तीसरी देन थी। तब से प्रविधि के क्षेत्र में इतनी तरक्की यानी विकास हुआ है कि सर्वोत्तम भूमि पर उसका प्रयोग किया जाय, तो हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता बेरोजगार हो जायेगी और उसे कहीं अन्यत्र काम देना पड़ेगा। इससे

सामाजिक और आर्थिक पुनः समझन—जिसके बिना विज्ञान तथा कृषि के बीच जो खाई है वह पाटी नहीं जा सकती—की नयी समस्याएँ सामने आयेगी।

अनुसंधान संस्थाएँ

देश का रूपान्तर करने में प्राविधिक विकास को सरकार कितना महत्व देती है यह तो इसी बात से परिलक्षित है कि उसने देश भर में अनेक अनुसंधान संस्थाएँ और सामग्री केन्द्र खोले हैं। इन संस्थाओं में हुई चन्द मौलिक और व्यावहारिक खोजों से बहुत ही प्रत्यक्ष मूल्य के परिणाम प्राप्त हुए हैं। पूसा गेहूँ अपने गुण, पौधों को होनेवाली बीमारियों के प्रति प्रतिरोध, प्रति एकड़ अधिक उपज और देश के विभिन्न भागों में पाई जानेवाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा बोआई आदि की अवस्थाओं के अनुकूल अपने को ढाल लेने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लोकप्रियता कृषकों तथा उपभोक्ता दोनों ने ही पिछले पचास वर्षों से भी कुछ अधिक से इसमें जो विश्वास प्रकट किया है, उस पर आधारित है। गन्ने के पतले डण्ठलवाली देशी किस्म के स्थान पर जिससे किसान को शरबत के रूप में बहुत कम यानी नगण्य-सी प्राप्ति होती थी, अब कोयम्बतूर किस्म का मोटे डण्ठलवाला गन्ना बोया जाने लगा है, जिससे प्रथम किस्म की तुलना में ५० प्रतिशत से ज्यादा अथवा उससे भी अधिक प्राप्ति होती है। इस नयी पद्धति का प्रभाव चीनी के कारखानों की स्थापना और उनसे ग्रामीण आबादी को जो रोजगारी प्राप्त होती है, उसके कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है उससे परिलक्षित होता है।

ज्वार, बाजरा आदि जैसे मोटे अनाजों के सम्बन्ध में अधिक उपज की प्राप्ति करवानेवाली किस्मों का पता लगाने के लिए ज्वार और बाजरे की खेती में विजातीयकरण-तकनीक का विस्तार किया जा रहा है अर्थात् यह विधि लागू की जा रही है। अनेक केन्द्रों में उक्त प्रकार के मोटे अनाजों के बारे में उन्नत कृषि-शास्त्र सम्बन्धी पद्धतियों का अध्ययन किया जा रहा है। कपास अन्वेषण के क्षेत्र में केरल में एण्ड्रूज की 'सी आय-लैण्ड' कपास का वायुजलानुकूलन एक उल्लेखनीय कदम है। मद्रास और पंजाब में अति लम्बे रेशे की कपास का पता लगाया जा चुका है और व्यावसायिक आधार पर उसका उपयोग करने की सिफारिश की गयी है। विजातीय मक्का बीज उत्पादन का एक विस्तृत कार्यक्रम हाथ में लिया जा चुका है और आलू तथा कसावा की सूजी आदि जैसे सहायक खाद्य पदार्थों एवम् टमाटर व बैंगन जैसी साक-भाजी और अगूतन पीते जैसे फलों तथा दालों एवम् तिलहनो की कई उन्नत किस्मों का पता लगाया जा चुका है। विभिन्न फसलों में कितनी मात्रा में उर्वरक दिये जाय तथा उन्हें कितने जल की आवश्यकता होती है, इस सम्बन्ध में विस्तृत बातों की खोज की जा चुकी है। घास-पात पर नियंत्रण और रसायन छिड़क कर पौधों की रक्षा करने के लाभप्रद फल प्राप्त हुए हैं।

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मौजूदा कृषि समस्याओं के विस्तार के जरिए और विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी तथा जलवायु सम्बन्धी अवस्थाओं पर आधारित प्रायोगिक केन्द्र स्थापित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का राज्यो में अनुसंधान सुविधाएँ विस्तृत करने का कार्यक्रम है।

संयुक्त कृषि

इन सब बातों से पता चलता है कि भारत में ग्रामीण जीवन की गतिहीनता भग करने के लिए महान प्रयासों का आयोजन किया जा रहा है। किन्तु अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि कृषि में उच्च स्तरीय अनुसंधान करके ही सुधार को प्रश्रय नहीं मिलता। भारत में कृषि

विषयक अनुसंधान का स्तर पर्याप्त ऊँचा है और ससार के अन्य किसी भी विकसित देश के कृषि अनुसंधान-स्तर से उसकी तुलना की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अन्वेषण से प्राप्त फलों का ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इस सम्बन्ध में मुख्य कमजोरी हमारी समाज व्यवस्था में निहित है। कृषि में किसी भी प्रकार की तरक्की के लिए भूमि सुधार एक पूर्व-शर्त है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उत्पादन वृद्धि में खेतों का छोटा होना उतना बाधक नहीं है जितना कि उनका अलग-अलग छितरे हुए रूप में होना तथा फसल पद्धति। निश्चित फसल पद्धतिवाले बड़े-बड़े खेतों का सम्बद्ध सस्था के कृषक सदस्यों के संयुक्त प्रबन्ध के अन्तर्गत कुशलतापूर्वक एवं लाभदायक रूप में संचालन होना चाहिए। इससे गाँव को एक खेत का नया आकार प्राप्त होगा और इस प्रकार खेतों के क्षन-विक्षत छोटे-छोटे टुकड़ों का लोप हो जायेगा। एक ही समान फसल बोनेवाले व्यक्तियों के निकट साहचर्य से सहकारी मिलिक-यतवाले साधन-स्रोतों का सामूहिक तौर पर उपयोग करने का प्रोत्साहन मिलेगा और बेहतरीन उत्पादन के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा मिलेगी। नयी-नयी कुछ बातें स्वतंत्र रूप से अपनायी जा सकती हैं, किन्तु कुल मिला कर देखने पर अधिकांश बातें सहकारिताओं के माध्यम से ही अपनायी जा सकती हैं।

मानवीय पहलू

उत्पादकता बढ़ाने, सघन कृषि को बढ़ावा देने और लोगों को काम के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए विस्तार सेवा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। इस सेवा के बिना अनुसंधान से प्राप्त परिणामों को सरलतापूर्वक कार्यान्वित करने की अपेक्षा करना अवास्तविक है। जिन्होंने इस कार्य के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विचार नहीं किया है, वे अनुसंधान से प्राप्त मालूमातों को किसान जिस धीमी गति से अपना रहे हैं, उस पर आसानी से चिढ़ सकते हैं। इस समस्या ने कार्यकर्त्ताओं को भी चक्कर में डाल दिया है। इसके लिए मुख्यतः मानवीय पहलू उत्तरदायी प्रतीत होता है। मानवीय

पहलू के महत्व को समझ लेने पर अन्वेषण की एक नयी दिशा के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसका विकास किया जाना चाहिए और विस्तार अनुसंधान का यह एक अंग होना चाहिए। अनुसंधान से प्राप्त फल उपभोक्ता (कृषक) तक पहुँचाना और उपभोक्ता की समस्याएँ वापिस अनुसंधानकर्त्ता (वैज्ञानिक) तक लाना विस्तार सेवा का मुख्य कार्य है। कार्यशीलता का यह एक नया क्षेत्र है जिसके जरिये प्रयोगशाला और खेत के बीच के अन्तर की खाई पटनी चाहिए।

विस्तार सेवा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, उसका सक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा। सामुदायिक विकास की समस्याओं में शोधकार्य करने और उस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से केन्द्रीय सामुदायिक विकास मस्था की स्थापना सम्भवतः इस दिशा में प्रथम कदम था। नयी दिल्ली स्थित उच्च स्तरीय कृषि अनुसंधान के लिए लब्ध प्रतीष्ठ भारतीय कृषि अनुसंधान मस्था में हाल ही में एक स्वतंत्र कृषि विस्तार विभाग खोला गया है। प्रकृति विज्ञान और मनोविज्ञान तथा ग्रामीण समाज शास्त्र के विशेषज्ञों की सेवा-प्राप्ति का लाभ उक्त विभाग को उपलब्ध है। गृह अर्थशास्त्र तथा श्रव्य-दृश्य शिक्षा के विशेषज्ञ भी वहाँ हैं। विभाग उत्तर-स्नातकीय शिक्षा कार्यक्रम चलाता है। कृषि विस्तार के क्षेत्र में शोधकार्य करके एम ए और पीएच डी. की पदवी प्रदान करने की व्यवस्था भी विभाग में है।

बहुविध प्रयास

कृषिक विस्तार के क्षेत्र में शोधकार्य का ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़नेवाला है। कृषक तक अनुसंधान से प्राप्त परिणाम पहुँचाने के सर्वाधिक प्रभावकारी उपायों का विकास किया जा रहा है। अनुसंधान से जो नये मालूमात होते हैं उनके महत्व के सम्बन्ध में किसान की दिलजमई करने में प्रात्यक्षिक बहुत प्रभावशाली पाये गये। परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध पैदा करनेवाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक

पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। ऐसा पाया गया है कि कुछ खोजों को वे किसान सामान्य किसान की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह अपनाते हैं, जिनका सामाजार्थिक दर्जा यानी प्रतिष्ठा कुछ ऊँची होती है। किसान के दृष्टिकोण अथवा अनुकूलता और प्रतिकूलताओं, मूल्यों और मान्यताओं, आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं, परिवर्तन के प्रति ग्रहणशीलता और अभिप्रेरणों को प्रभावित करनेवाले अन्य महत्वपूर्ण पहलू मालूम करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। 'किसान द्वारा निर्णय' करने की दिशा में भी शोधकार्य हो रहा है।

नेताओं की भूमिका

वैज्ञानिकों द्वारा की गयी खोजों पर सिफारिशें स्वीकार करने में जन-नायकों की भूमिका पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा पाया गया है कि अभिनव कृषि में तथा उन्नत पद्धतियों कार्यान्वित करने और फलस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को उन्नत बनाने की दृष्टि से गाँवों में लोक-मन को प्रभावित करनेवाले जन-नायक बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान और उसके व्यवहार के बीच का अन्तर मिटाने के लिए नयी-नयी पद्धतियाँ अपनाने की दिशा में अनेक अध्ययन किये जा रहे हैं।

निस्संदेह भारत में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान हुआ है। देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसका बहुत प्रभाव पड़ना चाहिए था। किन्तु यह प्रभाव अपेक्षित रूप से नहीं पड़ा है। इन विभिन्न शोधों के मध्य समन्वय और सश्लेषण स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता है। आगे चल कर इन शोधकार्यों से प्राप्त परिणामों से देश की कृषि में सुधार होना चाहिए। अनुसंधान का यही औचित्य है, वैधता है। 'विस्तार सेवा' के जरिये यह प्रदान की जा रही है, जो कि एक सामान्य केन्द्र बिन्दू-यानी किसान-पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान का सश्लेषण कर रही है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास में योगदान देने के लिए किसान की अवस्था सुधरनी ही चाहिए।

नयी दिल्ली: ५ अगस्त १९६३

हमारे हड्डी स्रोत

शिशिर कुमार बराट

भारत सरकार द्वारा खाद्य और कृषि-कचरे के उपयोगार्थ जो समिति नियुक्त की गयी थी, उसने अनुमान लगाया कि भारत में कच्ची हड्डियों की वार्षिक उपलब्धि ३ लाख ६० हजार टन के करीब है, जिसकी कीमत लगभग ७ करोड़ रुपये होती है। इनमें से सिर्फ ३८ प्रति शत ही एकत्रित और प्रशोधित होती है। अतः हड्डियों की सघन सम्प्राप्ति आवश्यक है। समिति ने सिफारिश की है कि यथा सम्भव हड्डी उत्पादनो, जिसमें हड्डी-खाद भी शामिल है, के निर्यात की हर कोशिश की जानी चाहिए।

भारत हड्डी-स्रोत में परम रूप से काफी धनी है और इसके और भी विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। आमतौर पर यह अन्दाज लगाया जाता है कि मवेशी का शारीरिक वजन का एक-चौथाई हड्डियों का वजन होता है। भारतीय मवेशी का औसत वजन करीब १०० पौंड मान कर और उनके मृत्यु-अनुपात का अनुसार अनुमान ८ प्रति शत लगा कर हिसाब लगाने से सैद्धांतिक तौर पर हर साल २ करोड़ ४६ लाख मवेशी मिलेंगे, और अकेले उनसे ही १० लाख ९० हजार टन हड्डियाँ प्राप्त होगी। वहरहाल, असल में जितनी हड्डी मिलनी चाहिए, वह बहुत कम है। बड़े जानवरों की हड्डियाँ, खासकर वाभाविक मौत मरनेवालों की, व्यापारिक रूप से एकत्रित की जाती हैं, क्योंकि कसाईखाने में ये जानवर गोड़ी सख्या में ही आते हैं। भारत सरकार द्वारा खाद्य और कृषि कचरे के उपयोगार्थ जो समिति नियुक्त की गयी थी, उसने अनुमान लगाया कि भारत में कच्ची हड्डियों की वार्षिक उपलब्धि ३ लाख ६० हजार टन के करीब है जिसकी कीमत लगभग ७ करोड़ रुपये होती है। विभिन्न जातियों के जानवरों से होनेवाली उपलब्धि निम्न तालिका में दी गयी है

तालिका			
विभिन्न जातियों के जानवरों से प्राप्त कच्ची हड्डी (लाख टन में)			
जाति	मृत	कत्ल	कुल
मवेशी	२ ४९५	० ०९७	२ ५९२
भैंस	० ९५२	० ०६८	१ ०२०
घोड़े और टट्टू	० ०१३	—	० ०१३
ऊँट	० ०१७	—	० ०१७
कुल	३ ४७७	० १६५	३ ६४२

अनुमानित उपलब्धि

इनमें से अभी सिर्फ १ लाख ३६ हजार टन हड्डियाँ ही, जो कि कुल अनुमानित उपलब्धि की ३८ प्रति शत है, असल में देश की ९८ हड्डी चूरक इकाइयों में एकत्र और प्रशोधित की जाती है और बाकी सगठन की कमी के कारण बेकार जाती है। हड्डियों की सघन सम्प्राप्ति का कार्य, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम के जंगलों से, हाथ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों में मवेशियों और जंगली पशुओं की हड्डियाँ

भारी परिमाण में एकत्रित नहीं होने के कारण बेकार चली जाती है। हमारे देश में हड्डियों की पूर्ति लचीली नहीं है, क्योंकि अधिकतर इनकी प्राप्ति मृत्त पशुओं से होती है।

एकत्रीकरण की कठिनाइयाँ

मुख्य कठिनाई हड्डियों के एकत्रीकरण की है क्योंकि हमारा पशुधन देश के साढ़े पाँच लाख गाँवों में वितरित है। सच तो यह है कि बहुत से गाँव तो ऐसे हैं—जिनकी औसत मवेशी संख्या सिर्फ ३५० है। मवेशियों का मृत्यु-अनुपात करीब ८ प्रति शत मान कर इन गाँवों में पशु-शवों की वार्षिक उपलब्धि प्रति गाँव ३० से कुछ कम होती है। अतः यह प्रत्यक्ष है कि गाँवों में पशु-शवों की इस आकस्मिक पूर्ति के कारण ग्राम स्तर पर हड्डियों का प्रभावशाली एकत्रण संगठित करना कठिन होगा। बहरहाल यह कार्य गाँवों में ग्राम पंचायतों, सामुदायिक परियोजना प्रशासन, ग्राम शवच्छेदन केन्द्रों, आदि के जरिये सलाह संगठित किया जा सकता है। गाँवों में मरनेवाले जानवरों का प्रशोधन निकट के शवच्छेदन केन्द्रों में किया जाना चाहिए। गाँवों में मरनेवाले सभी पशुओं को एक निश्चित जगह में पहुँचाया जाना चाहिए।

खड विकास क्षेत्रों में क्रय केन्द्र भी खोले जा सकते हैं जहाँ कि आस-पास के ग्रामीण एकत्रित की गयी हड्डियों को समुचित दर पर, जो कि उनके लिए आकर्षक भी हो, बेच सके। अधिकाधिक एकत्रण तभी सम्भव है, जबकि इन प्राथमिक एकत्रकर्त्ताओं को ऊँची कीमत दे प्रोत्साहित किया जाय। एकत्रण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की एक ऐसी पद्धति निकाली जानी चाहिए जो कि प्राथमिक एकत्रकर्त्ता को पर्याप्त लाभ की गारंटी दे। अधिकांश मामलों में यह एकत्रणकार्य लाभदायक नहीं होता, क्योंकि माल-भाड़ा और परिवहन की दूरी बहुत ऊँची है।

फासफोरस युक्त खाद के लिए हड्डी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत है। सुपर फास्फेट में फासफोरस पेण्टोक्साइड (P_2O_5) होता है जोकि पानी में घुल जाता है और भारत के अधिकांश भाग की भूमि में फास्फेटयुक्त उर्वरक

के इस्तेमाल के लिए यह अधिक उपयुक्त है। यदि हड्डी उत्पादक क्षेत्र में ही व्यापारिक सलफ्यूरिक एसिड सस्ते में मिल जाय, तो उसका उपयोग हड्डियों को सुपर फास्फेट में, कम-से-कम स्थानीय उपयोग के लिए, बदलने हेतु सलाह किया जा सकता है। तथापि, देश के कई भागों में धार्मिक कारणों से हड्डी उर्वरक को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, यद्यपि आमतौर पर इसके इस्तेमाल में कुछ हद तक इसकी ऊँची कीमत भी बाधक है। विशेषकर दक्षिण में सन्सिडी आदि देकर हड्डी उर्वरक के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार और राज्य सरकारें राज्य सरकार के जरिये बेचे जानेवाली हड्डी खाद की खुदरा कीमत पर २५ प्रति शत सन्सिडी देती है, हड्डी खाद तैयार उर्वरक के एक अंग के रूप में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है। यह वाछनीय है कि इस हड्डी खाद को एथरेक्स से बचाने के लिए अच्छी तरह निष्कीटित कर लिया जाय। जहाँ सुपर-फास्फेट आवश्यक न हो, वहाँ खनिजीय फास्फेटों का भी सुविधानुसार उपयोग कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा उपार्जन

देश में खनिजीय फास्फेट स्रोतों की कमी होने की वजह से हाल के वर्षों में हड्डियों अथवा अधिक फासफोरस पेण्टोक्साइड रखनेवाले हड्डी उत्पादनों के मुक्त निर्यात के विरुद्ध आवाज उठायी गयी है। यह आप्रह किया जाता है कि देश के अन्दर फास्फेटिक उर्वरक की मांग की पूर्ति करने हेतु इसका निर्यात बन्द किया जाना चाहिए। तथापि निर्यातीत हड्डी अथवा आयातीत फास्फेट राक की फासफोरस पेण्टोक्साइड इकाई की गणना के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय दर का अन्तिम विश्लेषण करे तो यह मालूम होगा कि सुपर फास्फेट के मामले में फासफोरस पेण्टोक्साइड का मूल्य बहुत प्रतियोगात्मक है। सच तो यह है कि प्रति टन फासफोरस पेण्टोक्साइड हड्डी अथवा हड्डी उत्पादन के रूप में निर्यात करने पर उसके बदले में आयातीत फास्फेट राक में वह तीन गुना अधिक मिलता है। अतः हड्डी उत्पादनों की वर्तमान अन्तर्रा-

ष्ट्रीय दर पर भारत के लिए इनका अधिकाधिक निर्यात करना लाभदायक है और देश की मांग की पूर्ति के लिए फास्फेटिक राक का आयात किया जाना चाहिए, जोकि विदेशों में तैयार मिलते हैं, उपर्युक्त तथ्यों के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने अधिकृत रूप में यह सिफारिश की है कि जब तक विदेशों से हमें फास्फेट राक सहज ही मिल जाता है और अपने देश के अन्दर हड्डी उत्पादनो का मुख्यतः खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, तब तक जितना ज्यादा सम्भव हो हम हड्डी उत्पादनो का, जिसमें हड्डी चूरा भी शामिल है, निर्यात करने की भरपूर कोशिश करें। इससे उपाजित विदेशी मुद्रा का एक भाग फास्फेट राक अथवा हाइपर फास्फेट जैसे खनिजीय फास्फेट का आयात करने में खर्च किया जा सकता है, जोकि हड्डियों तथा हड्डी उत्पादनो के निर्यात से फासफोरस पेण्टोक्साइड के होनेवाले नुकसान की पूर्ति करेगा।

चूना निकालना

हमारे देश में हड्डी उद्योग तो काफी हद तक अभी निर्यात-मुखी है ही, क्योंकि अभी सालाना औसत ७४ हजार टन हड्डी और हड्डी उत्पादनो का इंग्लैंड, बेल्जियम अमेरिका आदि को निर्यात कर करीब २ करोड़ ५० लाख रुपये की आय होती है। इसके अतिरिक्त, भारत प्रति वर्ष करीब ३२ से ३५ हजार टन हड्डी खाद तैयार करता है। परन्तु अभी इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध हटा दिया जाय तो इस उद्योग की विदेशी मुद्रा अर्जन क्षमता बहुत बढ़ जायगी। इससे प्राथमिक उत्पादको को अधिक लाभ होगा और जिससे कि उपलब्ध स्रोतों से अधिकाधिक हड्डी एकत्रण कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा।

हड्डी का अन्य उपयोग है इसे ओसीन में परिवर्तित कर देना और फिर यदि आवश्यक हो तो जिलेटिन में। हड्डी को श्लेष-जनीय अन्तर्द्रव्य कह सकते हैं, जिसमें कैल्शियम फास्फेट की लगभग-रचना का अणुस्फटा-त्मक अप्राणारिक क्रम रहता है, लेकिन उसमें अन्य

अयन भी रहते हैं। इसलिए जब हड्डी को कमरे के तापमान पर मन्द हाइड्रोक्लोरिक एसिड का संयोग कराया जाता है तो मुख्यतः ओसीन और मन्द हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कैल्शियम फास्फेट का घोल प्राप्त होते हैं। प्रयोगिक तौर पर यह पाया गया है कि हड्डी का चूना निकालने के लिए करीब १४ प्रति शत अम्ल आवश्यक है, और अम्ल को चूना जल अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर क्लीबित करने से कैल्शियम फास्फेट प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का भी उत्पादन होता है और उन्हें पानी से धोकर आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। परिवर्तन समु का सावधानी से फेर-बदल तथा क्लोराइडो को निकाल कर उचित रूप में शुद्ध डाइकैल्शियम फास्फेट प्राप्त करना सम्भव है।

नये मार्ग

अभी देश के अन्दर जिलेटिन की खपत कम है तथा इसके निर्माण की संस्थापित क्षमता का काफी भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है। अतः ओसीन और तकनीकल जिलेटिन के निर्यात व्यापार की क्षमता को जानना होगा और यदि इन उत्पादनो की ठीक मांग हो तो देश में ही प्राप्य हड्डियों से ओसीन और जिलेटिन तैयार करने के लिए कदम उठाने होंगे। अभी जापान भारी मात्रा में ओसीन आयात करने को तैयार है और हमारे यहाँ उपलब्ध उनकी अपेक्षा सस्ते श्रम को देखते हुए हमें इस मामले में अच्छी तरह प्रतियोगिता करने योग्य होना चाहिए। फिर, हड्डी को ओसीन में परिवर्तित करने से क्लोरिन उपयोग का नया मार्ग निकलेगा, जिससे माल-भाड़ा खर्च तो काफी बचेगा ही, साथ ही सह-उत्पादन के रूप में डाइकैल्शियम फास्फेट और अवशिष्ट आसव प्राप्त होगा जिनका उपयोग उपयोगी उर्वरको के रूप में करने के अलावा अन्य औद्योगिक कार्यों में भी किया जा सकता है।

ग्रामीण रोजगारी और योजना

चित्तप्रिय मुखर्जी

यदि हम एक आत्म-निर्भरक, अपने पेट पर खड़े होनेवाले स्वावलम्बी ग्राम समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो गैर खेतिहर उद्योगों के संगठित निजी क्षेत्र और ग्रामोद्योगों व गाँवों, यत्र-प्रधान और भ्रम प्रधान उद्योगों, तथा सामान्यतः शहरोन्मुख औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था और ग्रामोन्मुख विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के मध्य मत्तुलिन सम्बन्ध सुनिश्चित करना आवश्यक है।

तृतीय योजना के अन्त में पूर्ण तथा अर्ध-बेरोजगारों^१

की संख्या के द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंत की संख्या से भी अधिक होने के आधार हम में से अनेकों को उलझन में डालनेवाले प्रतीत होते हैं। दो दशकों की अवधि में बलिदान करते और कष्ट झेलते हुए क्या हमने एक ऐसे समाज का मार्ग प्रगस्त नहीं किया है, जिसमें बेरोजगारी तथा उसके सहगामी असमान सम्पत्ति वितरण की समस्या नहीं होगी? क्या स्वयम् योजना में या उसके कार्यान्वयन में कोई कमी है?

हितों में अनेकरूपता

फलविहीन विश्वयुद्ध के साथ समाप्त होनेवाले दीर्घ कालीन आर्थिक शोषण और हम पर थोपे गये देश विभाजन के फलस्वरूप चूर-चूर कर खोखलेपन की स्थिति तक पहुँचे हुए देश के सामने आज जो अनेक समस्याएँ-भूमि की उर्वरकता को मात कर देनेवाली जन-संख्या में अचानक वृद्धि से लेकर विनियोजन की

वांछित दर के साथ-साथ आगे बढ़ने हेतु घरेलू बचत की असफलता तक—हैं उनमें जन-शक्ति रूपी पूँजी का पूर्ण उपयोग करने के लिए अवसरों (काम के अवसरों) का अभाव निस्सन्देह सबसे भारी समस्या है। नवीन और प्राचीन तथा बड़े-बड़े शक्ति शहरों व नगरों में संगठित एकाधिकारवादी विकास और बिल्कुल असंगठित एवम् यत्र-तत्र बिखरे हुए कृषि विभाग के विलक्षण और अनुरूप संयोग से पीड़ित हमारे समाज ने—जिसके सामाजिक व आर्थिक जीवन में पहले से ही किसी न किसी रूप में व्यक्तिवाद तथा वर्ग-भेद की अन्तर्निहित भावना थी—गरीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी, शिक्षित और अशिक्षित, बाबूगिरी का काम करनेवालों व बुद्धिजीवियों और मेहनतकश के बीच हितों की अनेकरूपता तथा दृष्टिकोण भिन्नता को पतपाया।

आज जो देश अच्छी और सुदृढ़ स्थिति में है, उनके द्वारा निर्धारित समाधान (जो कि अधिकांश आकस्मिक रूप से, केवल युद्धकाल^२ में ही अपनी

१ “द्वितीय पंच वर्षीय योजनाअधि में ८० लाख व्यक्तियों को रोजगारी देने के नये अवसर निर्मित किये गये, जिनमें से ६९ लाख कृषि क्षेत्र के बाहर थे। द्वितीय योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या ९० लाख थी। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों का सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता जिनके पास कुछ काम तो है पर वे और भी अतिरिक्त काम करने के लिए उत्सुक हैं। फिर भी, उनकी संख्या डेढ़-दो करोड़ के बीच मानी जाती है।...तृतीय योजना के दौरान करीब और पौने दो करोड़ व्यक्ति अम-

शक्ति में शामिल हो जायेंगे। ऐसा अनुमान है कि तृतीय योजना के दौरान १ करोड़ ५ लाख नये व्यक्तियों को गैर खेतिहर कामों में तथा कृषि में और ३५ लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा।” —तृतीय पंच वर्षीय योजना; पृष्ठ १९६-१९९।

२ “ऐसे व्यक्ति भी हैं जो प्राविधिक बेरोजगारी की सम्भाव्यता से इन्कार करते हैं। जिस तर्क पर उनकी दलील आधारित है वह कुछ हद तक सही है, लेकिन अधिक तर्कसंगत नहीं जान पड़ती। जब तक द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण मांग

बेरोजगारी की समस्या सुलझाने की बात सोच सकते हैं) शायद ही उन वास्तविक समस्याओं की तह तक पहुँच सके जो कि मात्र गुजर-बसर करने के स्तरवाली अत्यधिक अतिरिक्त जन-शक्ति और परिणामस्वरूप बचत के अभाव तथा उच्च उत्पादकता और रोजगारी के मध्य उद्देश्यों के संघर्ष से पीड़ित हमारे देश में एक दुष्चक्र बनाये हुई है। हमने इस महान कठिन काम में उस वक्त हाथ डाला है जबकि कम आबादीवाले महाद्वीपों में अपनी अतिरिक्त आबादी को भेजने की कोई गुंजाइश नहीं है—जो कि अग्रणी पाश्चात्य देशों के मामले में थी—और न आज शोषण व नियंत्रण के लिए उपनिवेश है तथा न ही साम्राज्य।^३

माल्थस (Malthus) के सिद्धान्त को सही न मान कर जब समूचा ससार उत्सुकतापूर्वक 'भूख से मुक्ति' अभियान में शामिल होता है, तो प्रायः समस्त 'अल्प-विकसित' देश एक साथ राष्ट्रीय आत्म-

निर्भरता की योजनाएँ चलाते हैं, और विश्व-व्यापार एक ऐसा मोड़ लेता है कि उससे 'तुलनात्मक लागत' के पुराने सिद्धान्त के आधार पर दूसरों के साथ विनिमय करने के लिए शायद ही पर्याप्त रूप में निर्यात योग्य उत्पादन हो। विदेशी सहायता की परिभाषा अथवा उसके उद्देश्य जो भी हो^४ अल्प-विकसित देशों को सहायता देनेवाले शक्तिशाली राष्ट्र, विश्व संगठनों द्वारा अन्य दिशाओं में किये जानेवाले प्रयासों की प्रायः अवहेलना करते हुए, अपने स्वयम् के संघ बना लेते हैं और फलस्वरूप अल्प-विकसित देश पहले जिन उत्पादनों का निर्यात करते थे उनका मूल्य गिरा देते हैं। फिर भी, उन तमाम आपदाओं के बावजूद जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने कुछ स्थूल परिणाम प्राप्त किये हैं, और कुल आबादी में कार्यकारी आबादी का अनुपात १९५१ के बाद भारत में बढ़ा है।^५

असामान्य रूप से बढ़ नहीं गयी, संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका था।

यदि ससार का सर्वाधिक सम्पन्न देश, जो सतति-निग्रह के जरिये लाखों और सम्भवतः करोड़ों की तादाद में श्रम-शक्ति में बढ़ती नहीं होने देता अपनी श्रम-शक्ति को काम में लगाये नहीं रख सकता तो यदि यात्रिक क्रांति का विलोम पक्ष कभी सामने नहीं आया होता, उस अवस्था में कितनी भयंकर बेरोजगारी होती?—ई टिम्बर ज़िमरमैन (Zimmermann) वर्ल्ड रिसोर्सेस एण्ड इण्डस्ट्रीज; पृष्ठ १००।

३ चीन की समस्याएँ तथा सम्भाव्यताएँ हमारे समान हैं, पर उसने विकास की जो पद्धति अपनायी है वह हमारे विकास का जो सिद्धान्त है उसमें मेल नहीं खाती। जापान ने इस सदी के प्रारम्भ से महान सफलता प्राप्त की थी। लेकिन वह भी उसका विस्तृत साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाने के बाद और पहले की अपेक्षा आबादी बहुत बढ़ जाने से आज अपने साधन-स्रोतों का पुनर्मूल्यांकन करने में व्यस्त है। "राष्ट्रीय स्तर पर यह महसूस करने, समझ लेने पर कि राष्ट्र जितनी आबादी का भार सह सकता है, उस अधिकतम सीमा तक उसकी जन-संख्या पहुँच गयी है, जापान में पिछले वर्षों में जन्मानुपात में जो महान गिरावट (प्रति एक हजार के पीछे सात) आयी या लायी गयी है उससे हर किसी को विश्वास

हो जाना चाहिए कि जो कुछ जापान में हुआ उसकी पुनरावृत्ति भारत में भी की जा सकती है।"—रिपोर्ट ऑफ दि कमीशन फॉर लेजीस्लेशन ऑन टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग; पृष्ठ ४१।

४ "प्रायः 'सहायता' शब्द का बड़ा उदार प्रयोग किया जाता है और इसमें वह विनियोजन अथवा उधार भी शामिल कर ली जाती है जो, उदाहरणस्वरूप, विकासोन्मुख देशों को यंत्रों तथा उपकरणों के मध्य-कालीन निर्यात के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त विकासोन्मुख देशों को फिलहाल जो सहायता उपलब्ध है—विशेष कर कुछ यूरोपीय देशों से—वह इतनी लघु कालीन है और उस पर व्याज दर इतनी अधिक है कि उसे सामान्य वाणिज्य-उधार से शायद ही अलग किया जा सके।" डाक्टर बी के मदान (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक) का 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन' के मई १९६३ के अंक में पृष्ठ ६०९ पर प्रकाशित ३० अप्रैल १९६३ को दिया गया भाषण।

५ भारत की जनगणना १९६१ (१९६२ का पेपर नंबर १) पृष्ठ ४०२ और ४०९, तथा स्टेटमेंट (विवरण) १५ और १६, पृष्ठ २२ और २३ (रोमन में)। १९५१ को आधार (१००) मान कर १९६१ में आबादी वृद्धि का सूचकांक १२१.६९ और कामगारों की वृद्धि का सूचकांक १३३.८१ था। यदि १९०१

सभी समस्याओं को एक साथ हल करने के महान् दुस्तर कार्य का सामना करते हुए और वैसे परिणाम प्राप्त करने के लिए कृत-सकल्प-जिनकी प्राप्ति में हमसे अधिक विकसित देशों को भी अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए ज्यादा समय लगा-हम एक ऐसी आयोजन तकनीक का अनुसरण करते आ रहे हैं, जो एक माने में अनुपम तथा कार्यान्वित करने में अधिक कठिन है। यदि अन्य तरीकों से उक्त तरीका धीमी यानी मन्द गतिवाला है, तो इसके साथ ही कार्यान्वयन की प्रक्रिया में यह कम कष्टदायक भी है और ज्यों ही हम इस अवसाद-उडान भरने या छलाग मारने की स्थिति-को पार करके 'आत्म-निर्भर' यानी अपने पैरों पर खड़े हो कर विकास करने की स्थिति पर पहुँच जायेंगे उसके बाद इसमें बहुत ही दूरगामी फल प्राप्त होने की सम्भावना है। प्राथमिकता किसे दी जाय ? इस प्रश्न पर कुछ लोग यह दलील देते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी धन, सम्पत्ति है उसके समान वितरण और सबको रोजगारी देने के सवाल को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरों का कहना है कि समान वितरण बाद में भी हो सकता है और यदि निकट भविष्य में तीव्र गति से सम्पत्ति के सृजन या अन्यथा सम्पत्ति-सृजन के लिए आधार निर्मित करने की प्रक्रिया में वर्तमान आय सम्बन्धी असमानताएँ कुछ और भी

बढ़ जाती हैं तो अन्तिम परिणामों के सम्बन्ध में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। वे आगे कहते हैं कि उत्पादन-तकनीक के सुधार के दौरान प्रत्येक देश में-विभिन्न कालों में-प्रारम्भिक तौर पर कुछ बेरोजगारी अथवा श्रम-विस्थापन हुआ है, लेकिन उसके बाद उत्पादन साधनों व रोजगारी का विस्फुरण, विस्तार हुआ है, होता है। ऐसा सुझाया जाता है कि जो परिवर्तन अब हम कर रहे हैं उनका मूल्यांकन चन्द नये उद्योगों या काम-धंधों के अतिरिक्त रोजगारी सम्बन्धी आकड़ों अथवा बेरोजगारी की परिमाणात्मक शब्दावली में ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका मूल्यांकन उस जीवन मार्ग के प्रति परिवर्तित, पुनः संस्कृत उपागम की गुणात्मक दृष्टि से किया जाना चाहिए जिसने आज तक बेरोजगारी, गरीबी और सम्पत्ति-सृजन के अपर्याप्त साधनों का दुष्प्रचक्र ही निमित्त किया है।

सफलताएँ

उत्पादकता, रोजगारी और सम्पत्ति के समान वितरण के प्रतिस्पर्धात्मक दावों के प्रवाह में अपनी नैया को खेतों में हमारे आयोजक दो पच वर्षीय योजनाओं के दश वर्षीय काल में पुनरुत्पादनीय चर सम्पत्ति^६ का एक ठोस आधार निर्मित करने और १९५१ से लेकर पाँच करोड़ व्यक्तियों को रोजगारी

को आधार (१००) स्वरूप माने तो आबादी का लुचकाक १९५१ में १५० ७० तथा १९६१ में १८३ ४० आता है, कुल कामगारों का प्रातिशत्य इसी काल में १२६ ५० से बढ़ कर १६९ १४ हुआ। कुल आबादी में कामगारों का प्रातिशत्य १९०१ में ४६ ६१; १९५१ में ३९ १०; और १९६१ में ४२.९८ था। रोजगारी के विकास पर योजना-परिव्यय का प्रभाव स्पष्ट है, दो योजनाओं में सार्वजनिक विभाग में हुए कुल परिव्यय (६५ अरब ६० करोड़ रुपये) में से सामान्य तौर पर कृषि कार्यक्रमों को १३ अरब ३१ करोड़ रुपये यानी खानों सम्बन्धी कार्यक्रम पर हुए खर्च के करीब २० प्रतिशत रुपये मिले, और उद्योगों को २६ ९ प्रतिशत, निर्माण कार्यों को ६ ३ प्रतिशत, यातायात, भाण्डारीकरण आदि को २८.४ प्रतिशत और सामाजिक सेवाओं तथा अन्यो को

१८.१ प्रतिशत धन मिला। कामगारों की विभिन्न श्रेणियों में हुई वृद्धि के लुचकाक से इसकी तुलना करने पर हमें पता चलता है कि १९५१ को आधार (१००) मानने पर कृषकों की वृद्धि का प्रातिशत्य ४० ८६; खेतिहर मजदूरों का १४ २१, बागानों, वनों आदि में लगे श्रमिकों का २९, घरेलू तथा निर्माण उद्योगों के काम में लगे कामगारों का ५७ ९७, निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों का ३९ ०४, वाणिज्य और व्यापार में ३ ८७, यातायात, भाण्डारीकरण, संचार में ३९ ७५ और तीसरी श्रेणी की सेवाओं या काम-धंधों में लगे व्यक्तियों का प्रातिशत्य ३२ ३५ था।

६. पुनरुत्पादनीय चर सम्पत्ति १९५९-६० में १ खरब ७० अरब ८६ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९६०-६१ में ३ खरब २१ अरब ६४ करोड़ रुपये तक बराबर हो गयी थी। इसी

अथवा लाभदायक काम-धंधे प्रदान करने तथा तृतीय योजना^७ में अनुपातिक रूप से और भी तीव्र गति से रोजगारी के लिए उपयुक्त प्रावधान रखने में समर्थ हुए हैं। यद्यपि चन्द हाथों में धन का सकेन्द्रण होने की अवश्यम्भावी प्रवृत्ति जारी है,^८ तथापि उन व्यक्तियों के हाथ से, जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन के दौरान विदेशी उत्पादकों का स्थान ले लिया है—और विकास-शील व्यय के अन्य हिताधिकारियों के हाथ से भी—अत्यधिक क्रय-शक्ति कम करने के लिए अनेक प्रकार के राज्य-कर-विषयक, वित्तीय और प्रशासनात्मक कदम उठाये तथा साथ ही साथ अपनाये जा रहे हैं।

प्रविधि और रोजगारी

यद्यपि विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि भारत में बुनियादी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प-रोजगारी की है, तथापि इस शक्ति का उपयोग करने के तरीकों के सम्बन्ध में बहुत मत-भिन्नता है। 'राहत' की प्रकृतिवाली रोजगारी की जैसे के तैसे रूप में भर्त्सना^९ नहीं की जाती, लेकिन जैसा कि अनुवर्ती अनुभव से प्रकट हुआ है उससे देश की समग्र उत्पादकता अथवा सम्पत्ति में शायद ही कोई वृद्धि हो, इस आशा से इस प्रकार की

रोजगारी का निर्माण या विस्तार करने के विचार को कि जब उसका विस्तृत रूप सामने आयेगा तो अपने विशाल पैमाने मात्र से ही वह उस चीज की प्राप्ति कर लेगा, जो कि 'उत्पादनशील' रोजगारी छोटे पैमाने पर प्राप्त कर सकती है, उन व्यक्तियों की ओर से शायद ही प्रोत्साहन मिले जो 'तत्काल' की अपेक्षा आगे की सोचते हैं तथा इस बात में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि प्रति कर्मी उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए बेहतरीन तकनीकों के व्यवहार से इन्कार करना स्वयम् 'प्रगति' की जड़ में कुल्हाड़ी मारना है। पहले से ही यह तर्क मानते हुए कि शांति के समय में विकसित देश बेहतरीन उत्पादन-तकनीकों का व्यवहार करके बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन करने में अभी तक समर्थ नहीं हुए हैं, बड़ा जोर देकर यह दलील दी जाती है कि यदि वे देश असफल रहे हैं तो इसका कारण श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्राविधिक सफलताएँ प्राप्त करना इतना नहीं है, जितना कि मानवीय संस्थाओं तथा वृत्तियों का असफल होना, जिनसे मार्गदर्शन मिलता है एवम् जिन पर मानव व मशीन^{१०} का उपयोग करने के बड़े भारी काम का उत्तरदायित्व है।

काल में कुल चर सम्पत्ति अनुमानतः क्रमशः ३ खरब ४९ अरब ४० करोड़ और ९ खरब २४ अरब ५ करोड़ रुपये मूल्य की थी—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन; जनवरी १९६३।

७ महापञ्जीयक और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा १९६१ में लगाये गये अनुमान के अनुसार हमारी आबादी १९६६ में बढ़ कर ४९ करोड़ २० लाख; १९७१ में ५९ करोड़ ५० लाख और १९७६ में ६२ करोड़ ५० लाख तक हो जानेवाली है, इस काल में श्रम-शक्ति वृद्धि ७ करोड़ हो सकती है, मोटे तौर पर यह तृतीय योजना में करीब १ करोड़ ७० लाख, चतुर्थ योजना में लगभग २ करोड़ ३० लाख और पंचम योजना में तकरीबन ३ करोड़ हो सकती है।—तृतीय पंच वर्षीय योजना; पृष्ठ १५६, ७५०।

८ टेलिफ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन; मितम्बर १९६२।

९ इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा रोजगारी का विस्तार करने के लिए १९५२ में जिस 'ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम' की घोषणा की गयी थी, उसका उल्लेख किया जा सकता है। उत्पादनशील रोजगारी निर्मित करने के लिए 'अरुढिवादी' तरीकों का इस्तेमाल करने सम्बन्धी प्रस्ताव की अनेक अर्थशास्त्रियों ने उसे बेरोजगारी के समान ही कह कर आलोचना की है।—भवतोष दत्त एसेज इन प्लान इकनॉमिक्स में 'अनएम्प्लॉयमेण्ट एण्ड अनऑर्थोडोक्स मेथड्स' शीर्षक लेख।

१० "मार्गावरोधक यन्त्र युग का नहीं, बल्की द्रव्य-विषयक युग का अस्तित्व है। कामगार असहाय रूप से मशीन से बधा हुआ है और हमारी संस्थाएँ तथा रीति-रिवाज मशीनों से इस लिए आक्रांत एवम् अपक्षरित होते हैं कि यन्त्र का उपयोग पैसे के लिए होता है। हम उस प्राचीन पंथ से चिपटते हैं, वे विचार और भावनाएँ अभिव्यक्त करते हैं, जिनका

सरकारी दृष्टिकोण^{११} परिपूर्णत उक्त सिद्धान्त को स्वीकार करता है—और, स्वयम् योजना आयोग द्वारा स्वीकृत चन्द अपरिहार्य प्रशासनात्मक मन्दता को छोड़ कर—तथा यत्रो के आयात व निर्माण पर बड़ा जोर देता है, विशेष कर उन उद्योगों के लिए जो पूँजी-प्रधान होने चाहिए और उम गति से उत्पादन करे कि फलत न केवल घरेलू माग पूरी हो, बल्कि निर्यात के लिए भी पर्याप्त सामान बचा रहे। जैसा कि पिछले दशक के रिकार्ड से पता चलता है कि यत्रो का आयात अन्य प्रकार की आयातित वस्तुओं से बहुत अधिक हुआ है और वर्तमान विदेशी मुद्रा के संकट का कारण भी बहुत कुछ इन यत्रो का आयात ही है, जो भविष्य में उत्पादकता-वृद्धि के लिए निम्नदेह एक ठोस आधार निर्मित करता है।^{१२}

विविध उद्योग

इसके साथ ही योजना आयोग अतिरिक्त जन-शक्ति^{१३} को काम देने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर

भी विचार करना है और साथ ही साथ कुटीरोद्योगों के 'कृषि-प्रकार' 'घरक उद्योग', 'सेवा प्रकार' के कुटीर उद्योग आदि तथा सम्बद्ध कुटीर एवम् लघु-स्तरीय उद्योगों पर जोर देता है, जोकि अपेक्षा की जाती है कि प्रारम्भिक अवस्था में उपयुक्त सरक्षण प्रदान करने पर पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता सामग्री उत्पादित कर सकते हैं तथा प्रति कर्मी मामूली विनियोजन से काफी सख्या में पूर्ण और अर्द्ध-बेकार जन-शक्ति को काम दे सकते हैं। परम्परागत या अम्बर चरखा, हाथ करघा आदि को प्रोत्साहन देना, और सगठित क्षेत्र के साथ 'संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम' बनाना पिछले दशक में उठाये गये तथा तृतीय एवम् अनुवर्ती योजनावधियों में सघन रूप दिये जानेवाले कदमों यानी उपायों के प्रमाण है।

गाँवों में रोजगारी की समस्या

गाँवों में बेरोजगारी की समस्या जितनी बड़ी और जिम प्रकार की है, वह तो है ही, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण

हमारे जीवन की वर्तमान कार्यशीलताओं पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी निष्ठा पर रुपयेपैसे सम्बन्धी लाभ-हानि का भूत छाया हुआ है।"—जॉन डिवे (Dewey) दि हाउस डिवाइडेड अगेन्स्ट इटसेल्फ।

११ बेगारी की समस्या और उसके समाधानार्थ तीन उपायों—लघु उद्योगों के जरिये काम का विस्तार करने के लिए रोजगारी के अवसरों का विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण और औद्योगीकरण तथा ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम का सगठन—के प्रसंग में योजना आयोग का मत है, "उत्पादन की नयी तकनीकों का समावेश करने पर शुरू की अवस्था में रोजगारी में कमी भी हो सकती है। यह अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पुन प्राण फूँकने की दृष्टि से उल्लेखनीय दूरगामी फल प्राप्त होंगे,"—तृतीय पंच वर्षीय योजना, पृष्ठ, १९१।

१२ सन् १९५८-५९ और १९६१-६२ के दौरान हम ने अनुमानतः कुल ४० अरब रुपये की आयातित सामग्री में से १२ अरब रुपये के यत्र तथा सभी श्रेणियों के यातायात उपकरणों का आयात किया।

१३ तृतीय योजना के दौरान अतिरिक्त गैर खेतिहर रोजगारी का

अनुमान लगाते हुए (कुल १ करोड़ ५ लाख ३० व्यक्तियों को काम देने की सख्या में से ६७ लाख ५० हजार की प्रत्यक्ष रोजगारी के लिए गणना की जा सकेगी और शेष ५६ प्रतिशत विकास कार्यक्रमों के परोक्ष हिताधिकारियों के रूप में वाणिज्य तथा व्यापार में काम प्राप्त कर सकेंगे) योजना आयोग ने नव निर्माण कार्य, पहले से जारी कार्य और परोक्ष रोजगारी के सम्बन्ध में भी रोजगारी के लिए अमूमन तौर पर रोजगारी-निवेश-अनुपात का हिसाब लगाया है। नव निर्माण कार्य में रोजगारी के लिए (१) सिचाई परियोजनाओं में प्रति एक करोड़ रुपये के पीछे ७,००० मनुष्य-वर्षों का अनुपात है, (२) शक्ति परियोजनाओं में प्रति एक करोड़ रुपये के पीछे १,६०० मनुष्य-वर्षों का, और (३) यातायात निर्माण—विशेष कर रेल्वे में—१,९०० मनुष्य-वर्षों का अनुपात है। पहले से जारी रोजगारी के सम्बन्ध में स्वभावतः बहुत भिन्न, विस्तृत अनुपात प्रयुक्त होता है। लघु-स्तरीय उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगारी देने का मतलब है औसतन ९,००० रुपये का निवेश, दस्तकारियों के सम्बन्ध में इसका अर्थ है १,५०० रुपये का निवेश और रेशा तथा रेशम उद्योग के लिए अमूमन तौर पर १,०००

बर्बादी को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जानेवाले हैं, उनसे वह दूर नहीं हो सकेगी। यह मानते हुए कि परिवार नियोजन के लिए जो सोद्देश्य कदम उठाये गये तथा उठाये जा रहे हैं उनसे निरपेक्ष रूप से बढ़नेवाली आबादी का कुछ अंश ही प्रभावित होगा। हमारे सामने समस्या—जहाँ तक उत्पादन तकनीक का सवाल है—इस प्रकार के उत्पादनों के सम्बन्ध में पूँजी-प्रधान उपकरणों और जन-शक्ति

के बारे में अब प्राथमिकता निर्धारण की रहेगी जोकि—चन्द विशिष्ट प्रकार के भारी और बुनियादी उद्योगों अथवा अन्य ऐसे उपभोक्ता उत्पादनों^{१४} के विपरीत जिनके लिए निर्यात बाजार निर्मित करने की हमारी योजना है—त्रिशकु के समान बीचवाली स्थिति में है। सभी क्षेत्रों में प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने का सामान्य विचार जबकि अविवादास्पद है वहाँ वर्तमान अल्प-रोजगारी-स्तर, औद्योगीकरण की स्थिति प्राप्त^{१५}

रहये। दीर्घ और मध्य स्तरीय उद्योगों के सम्बन्ध में भी अलग-अलग सिद्धान्त या कसौटिया होंगी। इस्पात उद्योग में आवश्यक प्रति व्यक्ति १,६०,००० रुपये, उर्वरक उद्योग में ४०,००० रुपये, यंत्रोपकरण उद्योग में २५,००० रुपये, भारी यंत्र निर्माण उद्योग में १,००,००० रुपये, कोयला खुदाई व मशीन उद्योग में ६०,००० रुपये विनियोजन का अनुमान है। (तृतीय पंच वर्षीय योजना—गुष्ठ ७५३-७५७)। द्वितीय योजना में प्रति कर्मी कुल १०,४०० रुपये का निवेश किया गया था। उसके समक्ष तृतीय योजना में ९,७०० रुपये का अनुमानित निवेश डाक्टर ए वैद्यनाथन (इन्फ्रीजिंग दि इम्प्लॉयमेंट पोटेसियल प्रॉब्लम्स इन दि थर्ड प्लान, ए क्रिडीकल मिसेलनी)। पश्चिम बंगाल के प्रावि-धिकाधिक सर्वेक्षण के मालुमातो के अनुसार १९६१-७१ के दौरान दीर्घ-स्तरीय उद्योगों के विकास से ७३,९०० व्यक्तियों को काम मिलेगा और विनियोजन होंगे २ अरब ३७ करोड़ ८२ लाख रुपये। इस प्रकार प्रति कर्मी विनियोजन ३२,२०० रुपये होगा। वर्तमान अभियांत्रिक उद्योगों के विस्तार में ३ अरब ८४ करोड़ ३० लाख रुपये के विनियोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इन उद्योगों में ३९,९०० व्यक्तियों को काम मिल सकेगा। प्रति व्यक्ति विनियोजन करीब १,०७,००० रुपये आता है। नये लघु-स्तरीय उद्योगों में ६,४०० व्यक्ति लग सकेंगे और विनियोजन होंगे ४१ करोड़ ६९ लाख रुपये। प्रति कर्मी निवेश करीब ६९,००० रुपये आता है। कुल मिला कर १,१९,८०० कामगारों को काम देने के लिए कुल पूँजी परिकल्प्य ६ अरब ६३ करोड़ ८१ लाख रुपये होगा, प्रति कर्मी विनियोजन ५७,००० रुपये आता है। पश्चिम बंगाल के राज्य सांख्यिकीय केन्द्र के भूतपूर्व निदेशक द्वारा लिखित 'ए डिजाइन फार डबलपमेण्ट आफ विलेज इण्ड-स्ट्रीज इन वेस्ट बंगाल' सी देखिए, पैराग्राफ १९ १-१९ ९। १४ परिवर्तनशील समय के साथ हम 'तितान्त मार्ग रहितवास्था'

से बाहर आ रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में पाश्चात्य विक्रेताओं ने प्राच्य-निवासियों पर दोषारोपण किया है। यद्यपि हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि 'भागो बनावटी रूप से निर्मित की जाती है' और आधुनिक उद्योगवेत्ता 'भाग के सृजन-कर्त्ता' हैं, फिर भी हम यथा सम्भव 'तेते पाँव पसारिये जेती चादर होय' के मुताबिक उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, जो कमी ऐम्पो-आराम की चीजे समझी जाती थी। और, हमसे निश्चय ही विस्पृत आर्थिक गतिविधि के लिए क्षेत्र निर्मित होता है।

१५ सन् १८०० में विश्व जन-संख्या का अनुमान ९० करोड़ ५६ लाख होने का लगाया गया था। यूरोप में १८ करोड़ ७० लाख, उत्तरी अमेरिका में ५७ लाख, मध्य और दक्षिण अमेरिका में १ करोड़ ८९ लाख, अफ्रीका में ९ करोड़ और एशिया में ६० करोड़ २० लाख की आबादी थी। सन् १९३६ में विश्व जन-संख्या २ अरब ११ करोड़ ५८ लाख थी और उक्त भूभागों की क्रमशः ५३ करोड़ ३० लाख, १४ करोड़ ३ लाख, १२ करोड़ ५२ लाख, १५ करोड़ १२ लाख और १ अरब १५ करोड़ ३३ लाख। यह अनुमान लगाया जाता है कि सन् २००० तक यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका की आबादी प्रायः स्थिर रहेगी, अफ्रीका और एशिया की जन संख्या क्रमशः २५ करोड़ एबम् १ अरब ९० करोड़ हो जायेगी।

“ किसी नवोदित राष्ट्र का औद्योगीकरण ज्यों ज्यों विरसित होता है, आगे बढ़ता है और खेतिहर आबादी का गैर खेतीहर आबादी के प्रति अनुपात घटता है, तो आर्थिक विकास के एक ऐसे बिन्दु पर पहुँचा जा सकता है जब कि प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादकता भी नियात योग्य अतिरिक्त माल की प्राप्ति नहीं करवा सकनी। ”—बर्ट्रैंड रिसोर्सेस एण्ड इण्डस्ट्रीज, पृष्ठ १५८।

करने से पूर्व बहुत अधिक जन-संख्या वृद्धि और अन्यत्र स्थानों में विक्रम के सन्दर्भ में हमारे निर्यात व्यापार का भविष्य बहुत उज्ज्वल न होने की दृष्टि में ऐसा लगता है कि हमें इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसे कौन-से क्षेत्र हैं जहाँ यात्रीकरण करना तथा पूँजी-प्रधान तकनीकों का अपनाता नितान्त परमावश्यक है और कौन-से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाय।

भूमि-उत्पादकता में वृद्धि

यद्यपि हम इस बात में बिल्कुल सहमत हो सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या अन्य यूरोपीय देशों के समान यात्रीकरण (पशु-शक्ति से चलनेवाले उपकरण नहीं बल्कि अचेतन शक्ति से संचालित उपकरण, जैसे ट्रैक्टर आदि) और विज्ञान का बेहतरीन उपयोग करने से न केवल हमारे लिए खाद्यान्न एवम् सम्पत्ति की प्राप्ति होगी, बल्कि आगे चल कर निर्यात करने के लिए अतिरिक्त सामग्री भी बच सकेगी और साथ ही साथ काफी संख्या में लोग गैर खेतिहर काम-धंधों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, तथापि वर्तमान अवस्था में यदि हमें, उदाहरणार्थ, कृषि क्षेत्र में किसी निश्चित श्रम तथा विज्ञान—जोकि निश्चय ही यात्री-

करण का पर्याय नहीं है—का उपयोग करते हुए उच्च उत्पादकता और उसी उत्पादकता के लिए श्रम की बचत करनेवाले यांत्रिक साधनों के प्रयोग के मध्य किसी एक का चुनाव करना हो तो सम्भवतः तरजीह प्रथम को ही दी जायेगी। जैसे हम बहुत आगे चल कर प्राप्त होनेवाले लाभों की चिन्ता न करते हुए लागत और श्रम-विस्थापन के आधार पर ट्रैक्टर, फसल कटाई मशीनों आदि के उपयोग को खारिज कर पुराने हल व बैलगाड़ी को तरजीह देते हैं, वैसे ही उन्नत बीज, उर्वरक, जल, संयुक्त खेती, बेहतरीन भूवारण—पद्धति, खेतों का आकार बढ़ाने आदि जैसी बातों से ऐसा लगता है कि हम यह अवश्यम्भावी बात स्वीकार करते हैं कि समस्या श्रम बचत करने की उतनी नहीं है जितनी की भूमि की उर्वरकता बढ़ाने की।

यात्रीकरण की समस्या

व्यस्त मौसम में लम्बे समय तक दिन भर कमर तोड़ देनेवाले श्रम-साध्य काम में लगे देश के अधिकांश कृषकों को जहाँ निस्संदेह आराम^{१६} की आवश्यकता है वहाँ इस बात से भी हर कोई सहमत होगा कि उनकी (और इसलिए समग्र देश की) सेवा अथवा इमदाद के लिए यह बेहतर होगा कि

१६ “सन् १८५० में साधारण अमेरिकी सप्ताह में ७० घण्टे काम करता था, आज वह ४३ घण्टे काम करता है। उस वक्त एक अमेरिकी कृषक १८ अश्व-शक्ति के बराबर पशु-शक्ति का उपयोग करता था, सन् १९४० में प्रति खेतिहर कामगार २७८ अश्व शक्ति के बराबर शक्ति का इस्तेमाल हुआ। इसमें यांत्रिक शक्ति २६३ और पशु शक्ति मात्र १५ अश्व-शक्ति के बराबर थी। सन् १९३९ में प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में १२२७ अश्व-शक्ति घण्टे था और कनाडा में १५७५, चीन में ०४६ तथा भारत में ०४९ अश्व-शक्ति घण्टे। यांत्रिक शक्ति का उपयोग कर एक कृषक २४ घण्टे में उतना काम कर सकता है, जितना कि उसके बिना काम करनेवाला दूसरा किसान १० दिन में करता है। श्रम की बचत करनेवाले साधन वहाँ सर्वाधिक फलीभूत होते हैं जहाँ उसकी कमी है। सामान्यतय यह कहा जा सकता है कि जहाँ

भूमि की पर्याप्तता है वहाँ यात्रीकरण सर्वाधिक उपयुक्त है और जहाँ भूमि अपेक्षाकृत कम है वहाँ खेती में विज्ञान का प्रत्यक्ष व्यवहार अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। यांत्रिक श्रम-बचतकारी साधन जन-शक्ति का स्थान लेते हैं और प्रति व्यक्ति अधिक क्षेत्र पर खेती करने में समर्थ बनाते हैं। विज्ञान प्रति एकड़, प्रति पौधा, प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाने की ओर अग्रसर करनेवाला है। विज्ञान कृषि को सघन बनाता है और यत्र उसका विस्तार करते हैं। प्रति एकड़ अधिक उत्पादकतावाले देशों में श्रम पर अधिक खर्च की कमी अश्व में कम भूमि के इस्तेमाल के रूप में क्षतिपूर्ति हो जाती है।”—**वर्ल्ड रिसोर्सेस एण्ड इण्डस्ट्रीज**, पृष्ठ १५८। अमेरिकन रिब्यू के जुलाई १९६३ के अंक के परिशिष्टांक—ब्यू पाइण्ट ऑन इकॉनॉमिक एट—में ई जे लॉग का ‘अल्प-विकासित देशों में भूमि-सुधार का आर्थिक आधार’ विषयक लेख भी देखें।

वर्ष के शेष महीनों में उन्हें जो मजबूरन बिना काम के बैठा रहना पड़ता है उससे मुक्ति दिलवायी जाय। अत्यन्त व्यस्त महीनों में आराम निस्सन्देह आवश्यक है लेकिन यदि इसका मतलब एक ओर ट्रैक्टर, फसल कटाई यंत्र तथा 'ईथन-तेल' पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है तथा दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों में बेरोजगारी फैलती है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हम वैसा कर ही नहीं सकते। इस सैद्धान्तिक सम्भाव्यता की बिना परवाह करते हुए कि हमारे पास निर्यात योग्य अतिरिक्त सामग्री बच सकेगी, हमें उक्त बात अव्यावहारिक होने की वजह से खारिज करनी पड़ेगी।

गैर खेतिहर उत्पादन के इस प्रकार के मदों पर उक्त तर्क का प्रयोग करते हुए, जिनमें यांत्रिकरण करने से समग्र उत्पादन में वृद्धि नहीं होती या जिनमें हमारी घरेलू मांग से अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल श्रम की बचत होती है, हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि हम किस हद तक विदेशी मुद्रा में कमी करने और अतिरिक्त बेरोजगारी निर्मित करने की दोहरी हानि बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तथ्य का

हमारी वर्तमान अवस्था से कोई ताल्लुक नहीं है कि इंग्लैंड या अन्य यूरोपीय देशों में भी इसी प्रकार की सक्रमणकालीन बेरोजगारी की स्थिति उन्नीसवीं शताब्दी^{१७} के प्रारम्भिक काल में आयी थी।

इस क्षेत्र में ऐसा लगता है कि अब तक जिस नीति का अनुसरण किया गया है उसमें कुल स्पष्टता का अभाव है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के सबध में पिछले दशक में हमने जो प्रयास किये हैं उनके बावजूद कुछ ऐसे कारणों की वजह से, जिन्हें समझा जा सकता है, हमारा ध्यान बड़े उद्योगों की ओर निर्देशित होता है। विकास की यह पद्धति बहुत कुछ उस पद्धति से मिलती है, जिससे हो कर पाश्चात्य देश गुजरे हैं।^{१८}

प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग

यह मानते हुए कि ग्रामीण औद्योगीकरण का सर्वोपरि इलाज बिजली है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकेन्द्रित औद्योगीकरण के लिए यह नयी सहायता नव सम्पत्ति निर्माण में लगे और उन उद्योगों का स्थान लेने में नहीं जोकि काफी तादाद में श्रमिकों को लगाये

१७ देखिए जॉन सेविल (Saville) **रूरल डिप्रोप्लेशन**

इन इंग्लैंड एण्ड वेल्स : १८५१-१९५१ (अध्याय एक—दि हिस्टोरिकल बैक ग्राउण्ड) “उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी खोज-वेत्ता जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उनमें श्रम की कमी, स्थान आधिक्य और समय की कमी की समस्याएँ मुख्य थीं। इस तमाम प्रगति के बावजूद दोनों महायुद्धों के बीच के बीच वर्षों की अवधि में अधिकांश काल में समूचे पाश्चात्य संसार में कृषि अत्यधिक दुरावस्था में थी, और उसे अप्राकृतिक साधनों के जरिये जैसे के तैस रूप में जीवित रखा जा रहा था।” — **वर्ल्ड रिसोर्सेस एण्ड इण्डस्ट्रीज**; पृष्ठ १९३।

१८ “निस्सन्देह आज के भारतीय जीवन में भूमि सम्बन्धी समस्याएँ सब चीजों के केन्द्र में निहित हैं। ग्रामीण आय में महान वृद्धि—और अपेक्षाकृत बेहतर वितरण—किये बिना उद्योग का परिपूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि भूमि सम्बन्धी गरीबी परिमाणों तक दृष्टि से विशाल आन्तरिक बाजार की प्रभावक मांग को बुरी तरह सीमित कर देती है और अनवरत

रूप से भूमिहीन अथवा अल्प-रोजगार प्राप्त ग्रामीण श्रमिकों की संख्या या तो पूर्ववत् बनाये रखती है अथवा उसमें वृद्धि करती है तथा इस प्रकार कामगार का पारिश्रमिक न्यून बनाये रखती है एवम् जीवनावस्था ऐसी बदतर कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, और जैसा कि स्वाभाविक परिणाम निकलता है उसकी कार्यक्षमता बहुत ही निम्न। इस क्रांति (भारत में) के प्रणेताओं, शहरी मध्यम वर्ग और नये व्यापारी उद्योगपतियों, के लिए मिले, कारखाने, बिजली घर ही बड़ी चीजें हैं और राष्ट्रीय गर्व का पोषण करती हैं। यह पर्याप्त रूप से वैध है। बशर्ते कि इससे उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य की अवहेलना न हो कि भारत के खेतों में ही उसका अन्तिम भविष्य निहित है और यह कि स्वयम् औद्योगिक विकास भी सुसंयोजित तथा सन्तुलित हो, जोकि फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इसका अत्यन्त असमान विकास सम्भवतः कुछ तो राष्ट्रीय देन के कारण है, लेकिन अधिकांशतः इसके सामाजिक इतिहास के कारण।”—ओ एच के स्पेट **इंडिया एण्ड पाकिस्तान**।

हुए हैं तथा समाज की चन्द आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। यह सच है कि नये उद्योगों और पुराने तौर-तरीकों से काम चलाते आ रहे उद्योगों के बीच बिल्कुल सही-सही सीमा निर्धारित करना कठिन है, फिर चाहे वे अलग-अलग सामग्री का इस्तेमाल करते हों अथवा एक समान माल का। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल की खोज से इंग्लैंड के कोयले की खानों का काम करनेवालों में बहुत बेकारी फैल गयी थी अथवा जर्मनी में मशीन-रजकों की खोज से भारत में 'इण्डिगो' की खेती समाप्त हो गयी थी, उसी प्रकार बिजली-चालित आग ग्रामीण बर्द के पुराने आरे का स्थान ले लेगा, कुम्भकारी के स्थान पर अल्युमिनियम आ धमकेगा या प्लास्टिक उद्योग के सामने धात्विक खिलौने बनानेवाला ग्रामीण घुटने टेक देगा, लोहे की चढ़े ग्रामीण लोहार का हक छीन लेगी, और इसी प्रकार मोटर गाड़ियाँ असह्य ग्रामीण बैल गाड़ियों को बेकार बना देगी।

जब हम यह देखते हैं कि हाथ धान कुटाई अथवा तेल घानी (या अन्य ऐसे ही 'कृषि प्रकार' के उद्योग जो अतिरिक्त सम्पत्ति के निर्माण में नहीं बल्कि कुछ निश्चित

तादाद में सामग्री का प्रशोधन करने में ही लगे थे) के स्थान पर पिछले कुछ वर्षों में 'डीजल' अथवा बिजली से चलनेवाले यंत्र (यद्यपि लघु स्तरीय उद्योग) आ गये हैं, जबकि सिफारिश या सुझाव १९ इसके विपरित थे, तो हमें कम से कम देश के अधिकांश भाग^{२०} के सम्बन्ध में महिलाओं की रोजगारी का सूक्ष्म निरीक्षण करके यह देखने की आवश्यकता है कि क्या पिछले दशक में सामाजिक अवस्थाओं में इतना परिवर्तन हो गया है कि आर्थिक कार्यशीलता के जिस क्षेत्र में पहले महिलाओं का नियंत्रण था उससे काफी सख्या में उन्हें हटा कर तथा मात्र पुरुषों पर निर्भर बना देना आवश्यक हो गया। यदि यह मान लिया जाता है कि "शुरू-शुरू में नव उत्पादन-तकनीकों के समावेश से रोजगारी कम हो सकती है, आशा है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पुनः प्राण फूँकने की दिशा में आगे चल कर उनका उल्लेखनीय लाभ सामने आयेगा" (तृतीय पंच वर्षीय योजना, पृष्ठ १६१) तो भी यह पूछा जा सकता है कि यदि परम्परागत उद्योगों का यात्रीकरण^{२१} जारी रहता है तो बाद में गैर खेतिहर क्षेत्र में किस प्रकार के काम-धन्धे उपलब्ध होंगे?

१९ ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग (द्वितीय पंच वर्षीय योजना) समिति (१९५५) ने आयोजित विकास की प्रक्रिया में और अधिक प्राविधिक बेरोजगारी से बचने की बात पर जोर दिया था। तृतीय पंच वर्षीय योजना (पृष्ठ ४४३) से यह प्रकट होता है कि १९५८ के चावल कुटाई उद्योग (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ निर्देश होते हुए भी उक्त अधिनियम के कुछ मुख्य श्रद्धे राज्यों में पूरे नहीं किये गये हैं। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की १९५१ की जनगणना (खण्ड ६, भाग १-ए रिपोर्ट) और 'ए डिस्मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंजेन इण्डस्ट्रीज इन वेस्ट बंगाल' (१९५९) के पृष्ठ १५४-१५५ भी देखिए। पश्चिम बंगाल में १९०१ में अनाज व दाल प्रशोधन उद्योग में १२,५०० पुरुष और १,९०,२८० स्त्रियाँ (कुल २,०२,७८०) थी, उनमें से १९५१ में २३,२७० पुरुष और ८,१४० महिलाएँ (कुल १,११,४१०) ही थीं। पश्चिम बंगाल में १९०१ में गैर खेतिहर वर्गों की १०,६१,८७६

महिलाएँ स्वावलम्बिनी थीं, १९५१ में उनकी सख्या घट कर ६,०९,१२२ हो गयी थी। दीर्घ स्तरीय उद्योगों में १९५१ में ८५,४५७ महिलाएँ ही थी, जबकि १९०१ में ६१,२०० थीं। यह अन्तर इतना बड़ा है कि उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। १९६१ में हुई पश्चिम बंगाल तथा अन्य कई राज्यों की जनगणना से भी उक्त तथ्य की परिपुष्टि होती है।

२०. भारत की जनगणना, १९६१ (पृष्ठ २९-३१-सख्या रोमन अक्षरों में-१९६२ का पेपर नम्बर १)। महिलाओं की रोजगारी में सामान्य वृद्धि होने के बावजूद—अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में—१९५१ से कुछ श्रेणियों के काम-धर्मों में उल्लेखनीय कमी आयी है तथा १९६१ में उस कमी की गति और भी तीव्र बन गयी।

२१. संयोगवश, अन्वर या परम्परागत चरखे में जो कुछ भी कमियाँ हो और निर्यात बाजार प्राप्त करने के लिए संगठित मन्ती मिलों में जो भी सम्भाव्यता हो, हमें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रतिवेदन ('रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन'

यह सच है कि पिछले चन्द वर्षों में कृषक आबादी के एक वर्ग ने—उस वर्ग ने जिसके पास पर्याप्त जमीन थी और उस पर वह बाजार में बेची जाने योग्य अतिरिक्त सामग्री पैदा कर सकता था—कृषि उत्पादन की कीमते अधिक होने के कारण कुछ नकद लाभ प्राप्त किया है। किन्तु उस रकम का इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जिनमें सभी ग्रामीण भाग ले सके, उपयोग करने के एक निश्चित और सुदृढ़ तथा सोद्देश्य प्रयास के अभाव में उन चन्द कृषकों की वह रकम या तो और अधिक जमीन प्राप्त करने (अधिकांशतः गरीबों द्वारा धनवानों को निराश हो कर बेची गयी जमीन) में अथवा ट्राजीस्टर रेडियो, तेल-फूलेल, साबुन तथा अन्य इसी प्रकार की फैंसी चीजें खरीदने में या फिर मुकद्दमेबाजी में जाती है। जहाँ यह स्वीकार किया जाता है कि ग्रामीणों को उन चीजों का इस्तेमाल करने का पूर्ण अधिकार है जिन तक आज तक शहरी व्यक्तियों की ही पहुँच थी (और जब तक गाँवों से अतिरिक्त आय प्रवाहित नहीं होती उद्योग नहीं फल-फूल सकते) तो भी औद्योगिक शहरो और खेतिहर ग्रामों के मध्य आज जिस प्रकार के व्यावसायिक सम्बन्धों की प्रवृत्ति है उससे यह बात सामने आती प्रतीत होती है कि असतुलन अब भी जारी है एवम् सामान्यतः उसका झुकाव ग्रामीणों के विपक्ष में ही अधिक है।

यदि चंद पैसेवाले ग्रामीण अपने गैर मौसम के, बिना कामवाले महीने चाहे जिस ढंग से व्यतीत करना बर्दाश्त कर सकते हैं तो भी अधिकांश भूमिहीन कृषकों और बहुत कम जमीन के मालिक किसानों के लिए ये

बिना कामवाले महीने भार-स्वरूप है तथा बिल्कुल बेकार जाते हैं।

यदि एक आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़े होनेवाले ग्राम समुदाय का विकास करता है तो जहाँ हम एक ओर सहकारिताओं^{२२} अथवा पंचायतों को लोकप्रिय बनाने की बात सोचते हैं वहाँ दूसरी ओर इसके साथ ही हमें सगठित निजी क्षेत्र और गैर खेतीहर उद्योगों और गाँवों, यत्र-प्रधान और श्रम-प्रधान उद्योगों, तथा अन्त में सामान्यतः शहरोन्मुख औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था व ग्रामोन्मुख विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था के मध्य सतुलित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि अनेक कदम बठाने पड़ेंगे, उपाय काम में लाने पड़ेंगे। यदि हम यह भी स्वीकार कर ले कि विश्व स्थिति ऐसी है कि उसमें हम गांधीजी या रवीन्द्रनाथ ठाकुर की योजनाएँ जैसे के तैसे रूप में कार्यान्वित करने की बात शायद ही सोच सके, तो भी यह कहना पड़ेगा कि यदि हम असह्य ग्रामों में नव जीवन संचार करने और ग्रामीण बेरोजगारी का उन्मूलन करने की बात सोचते हैं तो हमें 'अपरमावश्यक' उपभोक्ता सामग्री के सगठित दीर्घ स्तरीय उत्पादकों और लघु-स्तरीय तथा कुटीरोद्योगी उत्पादन, बिक्री और यात्रीकरण की सीमा के बीच एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचनी ही पड़ेगी।

संरक्षण

यहाँ यह तर्क उठाया जा सकता है कि इस आधुनिक युग में इस प्रकार का कदम उठाना समय की गति को उल्टा फेरना होगा। चूँकि हमें इस प्रतिस्पर्धा-

के मार्च १९६१ का अंक देखिए) से पता चलता है कि पिछले चन्द वर्षों में उद्योग पर विदेशी मुद्रा परिव्यय उसकी आय से निरन्तर रूप से अधिक हुआ है। किन्तु घरेलू बाजार में मिल वस्त्र हाथ करवा और खादी के विकास को अधिक कठिन बना देता है। विदेशी मुद्रा की बर्बादी रोकने और हाथ करवा वस्त्र के स्वस्थ विकास, इन दोनों ही दृष्टियों से हमारी निर्धारित नीति का घरेलू उपभोक्ता-नीति

के साथ एवम् मिल क्षेत्र का कुटीर क्षेत्र के साथ निकट संयोजन स्थापित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

२२ ग्रामीण उधार अनुवर्ती सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सहकारिताओं तथा सामान्य ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर शहरी व्यापारियों और साहूकारों, महाजनो का कितना भारी प्रभाव है। (देखिए, 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन,' नवम्बर १९६१।)

प्रधान युग में अपना अस्तित्व बनाये रखना है, उसमें जिन्दा रहना है, इसलिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उत्पादन तकनीकों को आधुनिक रूप देना ही चाहिए। यदि हम यह तर्क उन उद्योगों पर लागू करें जो देश में भलीभाँति जमे हुए हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इन सब उद्योगों को इनकी प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी प्रतिस्पर्धा के समक्ष जो 'सरक्षण' प्रदान किया गया वह आज जिस 'तुलनात्मक लागत' और 'श्रेष्ठ प्राकृतिक लाभ प्राप्ति' के नियम की जो दलील पेश की जाती है उसके तदनुरूप नहीं था। (अधिकांश यूरोपीय देशों के इस्पात उद्योग के इतिहास से पता चलता है कि तुलनात्मक लाभ प्राप्ति का अभाव होते हुए भी अनेक देशों ने इस्पात सयंत्र स्थापित करने के लिए सरक्षणात्मक उपाय अपनाये।) यदि हमारे चीनी उद्योग, मोटर, ट्रक आदि का निर्माण करनेवाले उद्योग तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के प्रति सरक्षण प्रदान नहीं किया जाता तो जीवित नहीं रह पाते। (और फिर, प्रारम्भिक लाभ प्राप्त होते हुए भी लकाशायर सरक्षण के बिना जीवित नहीं रह सका, पतन नहीं सका।) और, यदि उक्त मामलों में उन उद्योगों के पास उन्नत उपकरण उपलब्ध होते हुए भी सरक्षण अच्छा था तो फिर हमारे लघु स्तरीय एवम् कुटीर उद्योगों को भी, यदि वे देश में किसी निश्चित कमी की पूर्ति करते हैं तो, क्यों न सरक्षण प्रदान किया जाय ?

अल्प और पूर्ण बेरोजगारी का समाधान निकालना हमारी योजनाओं का एक उद्देश्य है, और हम अपने असह्य गाँवों में आत्मनिर्भरता (जहाँ तक वह आधुनिक अवस्थाओं के मुताबिक ठीक है) लाने के लिए वचनबद्ध हैं। दीर्घ स्तरीय उद्योग का विकास अपनी प्रकृति से ही सबको काम देने में असफल रहा है और यदि हम यह भी मान लें कि हमारा निर्यात व्यापार उस सीमा तक बढ़ जायेगा कि वह अधिक विस्तृत पैमाने पर लोगों को काम प्रदान कर सकेगा (प्रत्येक देश में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता आन्दोलन हमारे सामने वैसा अवसर नहीं आने देगा) तो भी हम परम्परागत कुटीरोद्योगों को समाप्त होने दे कर बेरोजगारी की समस्या हल करने की आशा नहीं कर सकते। उत्पादकता और रोजगारी के मध्य एक सतुलन स्थापित करना ही होगा, अब तक जिस नीति का अनुसरण किया गया है वह किसी हद तक अनिर्णयात्मक अर्थात् दुलमुल और स्वयम् असफलता कारक रही है। एक ठोस व सोद्देश्य नीति के अभाव में जिन ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना के लिए हम वचनबद्ध हैं तथा जिन्हें हम ग्राम्य-जीवन का केन्द्र बिन्दु मानते, समझते हैं उन्हें विकसित होने का शायद ही अवसर या समय मिले, और ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प-रोजगारी की समस्या भी उक्त प्रकार की नीति के अभाव में हमारी अर्थ-व्यवस्था पर एक घब्बा ही बनी रहेगी।

कलकत्ता : २६ जुलाई १९६३

उपनिषदों में वर्णित उन कथाओं से जिनमें ब्राह्मणों को क्षत्रियों के पास जाकर दर्शन का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने की बातें आयी हैं और फिर उपनिषद के उपदेशों की ब्राह्मण-धर्म से विभिन्नताएँ एवम् पाली ग्रन्थों में वर्णित लोगों के अन्दर दार्शनिक कल्पनाओं के संकेतों से यही अन्दाज लगता है कि क्षत्रियों के अन्दर आम तौर पर पर्याप्त दार्शनिक ज्ञान मौजूद था, जिसका उपनिषद-सिद्धान्तों के निर्माण पर निश्चय ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा होगा। इसलिए यह मत कुछ हद तक सही प्रतीत होता है कि यद्यपि उपनिषदों की पराकाष्ठा ब्राह्मणों के हाथों ही हुई, पर वे ब्राह्मण धर्म से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होते हुए भी उनकी रचना अकेले ब्राह्मण सिद्धान्तों की अभिवृद्धि से ही नहीं हुई, बल्कि पर-ब्राह्मण विचारों ने भी उनके सिद्धान्तों को आगे बढ़ाया होगा या उनके सन्निव्यास और परिमार्जन में लाभप्रद सहयोग दिया होगा।

सुरेन्द्र नाथ दास गुप्त : ए हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन फ़िलासफी; खण्ड १

ग्रामीण औद्योगीकरण में वैज्ञानिकों और अभियंताओं की भूमिका

मंजेश्वर सदाशिव राव

आधुनिक वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के सन्दर्भ में ग्रामीण उद्योगों के समक्ष दो किस्म की समस्याएँ हैं—एक औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के आर्थिक उद्देश्य से और दूसरी जन-स्रोतों के उपयोगार्थ सामाजिक उद्देश्य से सम्बन्धित है। प्रश्न है कि क्या विकेन्द्रित पद्धति की स्थापना के जरिये एक प्राणवान औद्योगिकी को मूर्त रूप दिया जा सकता है, जिसके लिए आधुनिक प्राविधिक विकास का योजित उपयोग करना आवश्यक है? यह काम सुव्यवस्थित अनुसंधान से हो सकता है। इसमें वैज्ञानिकों और अभियंताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

हमारी आर्थिक योजनाओं में ग्रामीण औद्योगीकरण एक विशालकाय परियोजना है और आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास का उपयोग करने की जटिल समस्याएँ प्रस्तुत करता है। फिर भी, प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में उद्योगों के ग्रामीण विभाग में शहर और अन्य विभागों के बनिस्बत कुछ ही औद्योगिक वैज्ञानिक, जिनमें अभियंता भी शामिल हैं, जुटाये जा सके हैं। इस बड़े अन्तर के कारण क्या है? ग्रामीण उद्योग विभाग के विकास के कार्य क्या है? ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रमों में वैज्ञानिक और तकनीकल जन-शक्ति को किस तरह प्रभावशाली ढंग से जुटाया जा सकता है? इन पर तथा सम्बन्धित अन्य प्रश्नों पर, जिनके लिए अब तक कोई मान्य हल नहीं मिला है, हमारी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण औद्योगीकरण की दीर्घ-कालीन समस्याओं के सन्दर्भ में, आधुनिक वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के दृष्टिकोण से, विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

दीर्घ-कालीन समस्याएँ

अन्य विभागों के उद्योगों से भिन्न ग्रामीण उद्योग औद्योगिक उत्पादन के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के सन्दर्भ में दो भिन्न किस्म की दीर्घ-कालीन विकास समस्याएँ प्रस्तुत करते हैं। पहली किस्म की समस्याएँ हर विभाग के उद्योगों में पायी जाती हैं

और उनका सम्बन्ध औद्योगिक कार्यों और प्रक्रियाओं की उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि होने से है ताकि आर्थिक अस्तित्व और प्रगति सुनिश्चित हो सके। ये मुख्यतः व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों अथवा ग्रामीण उत्पादकों की समस्याएँ हैं। आधुनिक सन्दर्भ में उनका एक ही हल है और वह है उपयुक्त आधुनिक प्राविधिक विकासों को अपनाना। उन्हें औद्योगिक उत्पादकता की समस्याएँ भी कह सकते हैं। तथापि ग्रामीण औद्योगीकरण अथवा गाँवों में औद्योगिक कार्यों के विस्तार की प्रक्रिया दूसरी किस्म की समस्याएँ भी प्रस्तुत करती है जो कि हमारी योजनाओं में ग्रामीण समुदायों में उद्योगों अथवा धंधों में अतिरिक्त रोजगारी के अवसर निर्मित कर जन-शक्ति के उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी गयी है, उससे पैदा होती है। ये मुख्यतः समूचे विभाग की समस्याएँ हैं जिनकी ओर योजनाधिकारियों का ध्यान आकर्षित है और ये इस विभाग के लिए विशिष्ट समस्याएँ हैं। इन्हें ग्रामीण औद्योगीकरण में जन-शक्ति के उपयोग की समस्याएँ कह सकते हैं। ये दोनों ही किस्म की समस्याएँ स्पष्ट हैं, क्योंकि इनके उद्देश्य, दृष्टिकोण और हल प्राप्त करने के तरीके अलग हैं।

विकेन्द्रित पद्धति

ग्रामीण उद्योग विभाग शहरी तथा अन्य औद्योगिक विभागों की अपेक्षा कम उन्नत है। इसके विकास की कोशिश ग्रामीण औद्योगीकरण के आयोजन और कार्यान्वयन के

जरिये की गयी है। आयोजन की दो बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व-शर्तें हैं सामान्य रूप से उपलब्ध रोजगारी से कहीं अधिक मात्रा में औद्योगिक रोजगारी निर्मित करना और उच्च औद्योगिक उत्पादकता का समावेश कर ग्रामीणों का जीवन-स्तर उच्च करना। विकासोन्मुख क्षेत्रों में औद्योगीकरण सामान्यतः विकसित क्षेत्रों में चलाये जा रहे औद्योगिक कार्यों के जरिये किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण सामान्यतः शहरी औद्योगिक पद्धति का विस्तार कर लाया जाता है। इस कार्य के लिए प्रारम्भिक तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त उद्योग हैं कृषि और सह-उद्योगों के कच्चे माल के प्रशोधन उद्योग। इन उद्योगों के शहरी अथवा आधुनिक रूप सामान्यतया बड़े पैमाने के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी तकनालाजी पूँजी प्रधान और कम रोजगारीवाली होती है। इन उद्योगों का गाँवों में विस्तार करने से औद्योगिक उत्पादकता की समस्याएँ हल हो सकती हैं, पर इससे अतिरिक्त रोजगारी के अवसर निर्मित करने की समस्या का हल नहीं हो सकता। इस प्रकार ग्रामीण औद्योगीकरण की शीघ्र और दीर्घ-कालीन सम्भावनाएँ औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के आर्थिक उद्देश्य और जन-शक्ति स्रोत के उपयोग के सामाजिक उद्देश्य के बीच मतभेद उपस्थित करती है। इस मतभेद को औद्योगीकरण की विकेन्द्रित पद्धति अपनाकर दूर करने की कोशिश की गयी है।

सैद्धान्तिक कल्पना

यद्यपि औद्योगीकरण की विकेन्द्रित पद्धति के विकास पर बहुत विचार किया गया है, परन्तु अब तक कोई ठोस रूप नहीं दिया जा सका है। इसका एक स्थिर रूप है आपेक्षिक तौर पर छोटे और लघु उद्योगों का ग्रामों में प्रसार तथा कुल रूप में रोजगारी में वृद्धि। तथापि इसका अधिक प्राणवान रूप यह मानना है—उपलब्ध स्रोतों का अनुकूलतम पैमाने पर आर्थिक लाभ उठाने और रोजगार प्रदान करने के लिए बँटवारा। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना अभी भी बाकी है कि क्या आधुनिक प्राविधिक विकास के दृष्टिकोण से सच्चे प्राणवान औद्योगिकी

के रूप में विकेन्द्रित पद्धति की स्थापना की जा सकती है? यद्यपि छोटे और लघु उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का विकास करने हेतु आर्थिक सहायता और सरक्षण जैसे आर्थिक साधनों को परमावश्यक माना जाता है तथापि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि इस पर विचार किया जाना चाहिए, कि इसमें भी बड़े उद्योगों की भाँति औद्योगिक वैज्ञानिकों और अभियंताओं का सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है या नहीं। यह सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक विकेन्द्रीकरण की समस्या को हल करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। परन्तु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के वर्तमान तरीके, इस प्रकार का अनुसंधान कौन-सी एजेंसियाँ करेगी तथा ग्रामीण औद्योगिक विकास के विशाल क्षेत्र में इसके परिणामों को प्रयुक्त करने के सन्दर्भ में यह नहीं बताया गया है कि अनुसंधान किस प्रकार का हो। इस प्रकार औद्योगीकरण की विकेन्द्रित पद्धति की कल्पना अभी मुख्यतः सैद्धान्तिक ही है, जो कि आर्थिक विश्लेषणकारों के लिए दिलचस्प विषय है परन्तु व्यावहारिक वैज्ञानिकों और अभियंताओं तथा ग्रामीण उत्पादकों के बड़े समूह के लिए अवधारणा के बाहर की बात है।

अनुसंधान और विकास

विकेन्द्रित पद्धति में वैज्ञानिकों और अभियंताओं की रुचि न होने के कारण कभी-कभी यह आलोचना की जाती है कि उनमें 'सामाजिक चेतना' नहीं है जो कि उन्हें ग्रामीण उद्योग विभाग की ओर पर्याप्त आकर्षित कर सके और इसकी विकास समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान करने के लिए प्रेरित कर सके। इस तरह की आलोचनाएँ अशत वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास से प्रभावित विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को पूर्णतः नहीं समझ सकने के कारण की जाती हैं। अशत यह औद्योगिक उत्पादकता की समस्याओं और ग्रामीण औद्योगीकरण में जन-शक्ति स्रोत के उपयोग को एक समान ही समझने से पैदा होती है। विज्ञान और तकनालाजी में हुई आधुनिक

प्रगति के सन्दर्भ में विकासोन्मुख गाँवों की वे समस्याएँ, जिनका सम्बन्ध अनुसंधान से है, तकनालाजी के उपयोग से सम्बन्धित है, न कि तकनालाजी के विकास से, जिससे सर्वाधिक आर्थिक और सामाजिक लाभ हो। इन समस्याओं को औद्योगीकरण के क्षेत्र में ही हल करना है।

दो-क्रमी प्रक्रिया

आलोचना से यह ज्ञात होता है कि अभी भी हमारे विचार में उन्नीसवीं सदी की “भौतिक विज्ञान बनाम सामाजिक विज्ञान” वाली अवस्था मौजूद है, यद्यपि इस प्रकार का द्विभाजन माध्यमिक विज्ञान और द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में ही सामाजिक उद्देश्यों में प्रयुक्त करने के लिए भौतिक और सामाजिक दोनों ही विज्ञानों से प्राप्त वैज्ञानिक तकनीक के विकास से कब की दूर हो चुकी है। आलोचना जिस अनुसंधान की बात करता है, वह अनुसंधान है जिसे आम लोग समझते हैं और जो बृहत् वैज्ञानिक खोजों और प्राविधिक अन्वेषणों से सम्बन्धित है। वर्तमान परिभाषा में इसे “अनुसंधान और विकास” कहते हैं। अनुसंधान और विकास अथवा विकास करनेवाला वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा औद्योगिक तकनालाजी की प्रगति ही वह मुख्य रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके जरिये आधुनिक उद्योग उच्च उत्पादकता प्राप्त करने की ओर प्रगति कर रहे हैं अथवा प्राकृतिक स्रोतों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित तथा औद्योगिक उत्पादनों की श्रृंखला विस्तृत करने के लिए अपनी क्रियाशीलताओं को विविध बना रहे हैं। यह दो-क्रमी प्रक्रिया है जो कि दो भिन्न माध्यमों द्वारा पूरी की जाती है। प्रथम क्रम में, जो कि व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वैज्ञानिक उद्योग में विज्ञान के नये उपयोग की खोज करते हैं। द्वितीय क्रम में, जो कि प्राविधिक विकास अथवा प्राविधिक अनुसंधान कहलाता है, औद्योगिक उपकरणों का निर्माण करनेवाले उद्योगों में काम करनेवाले अभियंता विज्ञान के नये तरीकों का उपयोग नयी तकनालाजी का विकास अथवा वर्तमान तकनालाजी में सुधार करने में करते हैं।

संगठित अनुसंधान और विकास के जरिये ही वर्तमान शताब्दी में विज्ञान और तकनालाजी में अद्भुत प्रगति की गयी है। अनुसंधान और विकास नये उद्योगों को आरम्भ करने और पुरानों को मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपेक्षिक तौर पर नये उद्योग, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप ही जन्मे हैं, वे हैं आधुनिक रसायन प्रशोधन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, एडवान्स इजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, आणविक उद्योग, आदि। पुराने उद्योग वे हैं, जिनका मूल पूर्व-औद्योगिक दस्तकारियों में है और जिन्होंने कि १७५० और १८५० के बीच औद्योगिक क्रांति में से गुजरने पर अपना कार्य बड़े पैमाने पर कर लिये हैं और उस तकनालाजी को ठोस कर लिया है जो कि प्रथम अभियांत्रिकी के उपयोग के जरिये विकसित हुई और बाद में प्राकृतिक रेशों का उपयोग करनेवाले वस्त्रोद्योग, वानस्पतिक तेल और स्नेह, चीनी, चमड़ा, कागज, कुम्हारी तथा अन्य कृषिक प्रशोधन उद्योगों, दुग्ध और खाद्य उत्पादनों जैसे उद्योगों को विज्ञान के उपयोग के जरिये अभिनव किया। ये पुराने उद्योग ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं क्योंकि प्रक्रियाएँ अपेक्षाकृत सरल हैं तथा कच्चे माल ग्रामीण स्रोत से ही उपलब्ध हैं।

चन्द गलतफहमियाँ

प्राविधिक रूप से अर्ध-विकसित उद्योग, जैसे कि हमारे परम्परागत ग्रामोद्योग, अनुसंधान और विकास के जरिये प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आधुनिकीकरण अथवा आधुनिक तरीकों को अधिकाधिक अपनाकर ही प्रगति कर सकते हैं। व्यावहारिक वैज्ञानिक और प्राविधिक अनुसंधान के तरीकों को औद्योगिक विकेन्द्रीकरण में युक्त नहीं किया जा सकता। प्राविधिक परिवर्तन के फलस्वरूप होनेवाले सामाजिक व्यवस्था की समस्याओं का हल करने में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः कभी-कभी जो यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण उद्योगों में किया जानेवाला अनुसंधान वैज्ञानिक

खोजो और प्राविधिक अन्वेषणों की दिशा में किया जाना चाहिए, जो कि आधुनिक तकनालाजी की अवाछनीय सामाजिक और केन्द्रित जटिलताओं से मुक्त हो, बेमतलब हैं। अनुसंधान करनेवाले वैज्ञानिकों अथवा अभियंताओं से ऐसी आशा करना उनसे किसी चमत्कार की ही आशा करना होगा। अधिकांश वैज्ञानिक खोजों और प्राविधिक अन्वेषणों के पीछे आर्थिक उद्देश्य हैं। सामाजिक जटिलताएँ उद्देश्य और जिस सन्दर्भ में मनुष्य द्वारा उसका उपयोग किया जाता है उसके फलस्वरूप पैदा होती हैं। यदि किसी तरह विकेन्द्रित पद्धति सफल हो सकती है तो वह सिर्फ आधुनिक तकनालाजी का उपयोग कर ही। इस असम्यक् भास को सिद्ध करने में अधिक समय नहीं लगेगा कि ग्रामीण उद्योगों में रोजगारी के जरिये जन-शक्ति स्रोत के उपयोग की समस्याएँ हमारी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में वैज्ञानिक और प्राविधिक अनुसंधान की कमी के कारण नहीं पैदा हुई हैं बल्कि इस कारण से पैदा हुई हैं कि हम यह समझने में असमर्थ रहे हैं कि किस तरह आधुनिक प्राविधिक विकास के रूप में उनके सग्रहित परिणामों को उपयोग में लाया जाय ताकि जितना संभव हो उतना उत्तम आर्थिक और सामाजिक परिणाम निकले।

आधुनिक तकनालाजी की जटिलताएं

आज हमारे सम्मुख जो समस्याएँ हैं वे शक्ति के यांत्रिक स्रोतों के प्राविधिक विकास से शुरू हुईं, जो कि औद्योगिक क्रांति की अवधि में सौ वर्ष से भी पूर्व आरम्भ हुईं। तब से विज्ञान और तकनालाजी ने बड़ी तीव्र गति से प्रगति की है। उनकी विकास गति आबादी-वृद्धि गति से भी काफी तेज रही है। हमारे समय में ही स्वचलन का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्राविधिक विकास, जिन्होंने कि दूसरी औद्योगिक क्रांति की रूपरेखा तैयार कर दी (साइबरनेटिक रिवोल्यूशन), के कारण पैदा हुई समस्याओं को हमारी औद्योगिक क्रांति को अभी भी झेलना बाकी है। इस दृष्टिकोण से यह समझना कि ग्रामीण उद्योगों की समस्याएँ तकनालाजी के विकासार्थ अनुसंधान की समस्याएँ हैं, बहुत ही कृत्रिम हैं।

तथापि यथार्थ दृष्टिकोण है उन्हें आधुनिक प्राविधिक विकास के साथ ही अन्य स्रोतों के योजित उपयोग की समस्याएँ समझना ताकि अनुकूलतम अथवा सर्वाधिक सम्भव रोजगारी के अवसर प्राप्त हो सकें। विकेन्द्रित पद्धति तथा “माध्यमिक” तकनालाजी की आधुनिक कल्पना इस अनुकूलतम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण औद्योगीकरण में आधुनिक तकनालाजी के योजित उपयोग का इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि शहरी उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कर बिना क्रम अथवा आयोजन के उपयोग किया जाय। आधुनिक तकनालाजी का उसी के द्वारा उठाया गया समस्याओं के हल के लिए उपयोग परस्पर विरोधी लग सकता है। परन्तु अगर यह महसूस कर लिया जाय कि आधुनिक तकनालाजी की सामाजिक जटिलताएँ इसमें निहित न होकर इसके उपयोग के तरीके पर निर्भर हैं तो कोई विरोधाभास नहीं है।

तकनालाजी का योजित उपयोग

हर विभाग में औद्योगीकरण विकसित विभागों से तकनालाजी के साथ-साथ सगठन की नकल कर किया जाता है। हमारी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में हर औद्योगिक विभाग इस्पात और मूल उद्योगों से लेकर लघु शहरी उद्योगों तक, उन्नत अथवा विकसित देशों की तकनालाजी अपना रहे हैं। ग्रामीण विभाग कोई अपवाद नहीं है। यह अधिक उन्नत शहरी विभाग से तकनालाजी अपना रहा है। यह विकेन्द्रित प्रक्रिया है, जो कि उत्पादकों के स्वयं के निर्णय से लागू किया गया है। सामान्य क्रम में उद्यमी उत्पादक को निर्णय करने में छोटी-छोटी आटा मिलों से लेकर बड़ी सोल्वेण्ट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स बनानेवाले औद्योगिक निर्माताओं से सहायता मिलती है। उसे तकनीकल ज्ञान नहीं होता और वह तकनीकल ज्ञान तथा औद्योगिक उपकरणों के लिए व्यावसायिक स्रोतों पर निर्भर करता है। सफल उत्पादकों के उदाहरण उनमें और विश्वास पैदा करते हैं। अतः उपलब्ध स्रोतों के उपयोगार्थ सर्वोत्तम

मार्ग का ध्यान रखे बिना ही औद्योगिक सगठन और तकनालाजी आमूल रूप से दोहराये जाते हैं। योजना का एकमात्र प्रभावशाली व्यूह है ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को उद्गम स्थल—सामुदायिक विकास खड स्तर—की ओर निर्देशित करना ताकि स्रोतों का, जिनमें जन-शक्ति और तकनालाजी भी शामिल हैं, अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

तकनालाजी सर्वाधिक योग्य स्रोत है और सम्पूर्ण रूप में औद्योगीकरण की प्राणवान प्रक्रिया में नियंत्रण योग्य स्वतंत्र परिवर्ती है, जबकि उसमें उत्पादन और रोजगारी में बचत निर्भरीय परिवर्ती है। यदि तकनालाजी पर नियंत्रण रखा जा सकता है तो रोजगारी पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। परन्तु नियंत्रण के लिए खड-स्तर पर तकनीकल सेवाओं के सगठन की जरूरत है, जिसमें औद्योगिक आयोजन के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, समाज वैज्ञानिकों और अभियंताओं की सेवाएँ भी शामिल हैं, जो कि भौतिक और समाज-विज्ञान के तरीकों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। इन तरीकों को ही प्रयुक्त कर प्राविधिक विकास का उपयोग योजित आधार पर उत्पादन खर्च में बचत करने और उच्च पारिश्रमिक पर अधिक रोजगारी देने में किया जा सकता है।

तकनीकल सेवाओं का संगठन

तकनीकल सेवाओं के इस तरह के सगठन के परिणाम-स्वरूप, जिसका कार्य पंच वर्षीय योजनाओं के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकसित हो रहे बहुत ही उन्नत उद्योगों को उपलब्ध तकनीकल और सलाह सेवाओं की तरह ही है, आधुनिक भौतिक और समाज विज्ञान की समस्त रचनात्मक शक्तियाँ धीरे-धीरे और निश्चल समाज में रहनेवाले हमारे लाखों लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में सहायक होगी। पचायत राज की स्थापना ने, जो कि ग्रामीण विकास आयोजन का अधिकार स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं को दिया है, उस पैमाने और गुण-स्तर पर इस तरह की तकनीकल सेवाओं का सगठन सम्भव बना दिया है

जो कि हमारे आर्थिक आयोजन के प्रथम दशक में सम्भव नहीं था।

औद्योगिक आयोजन

औद्योगिक आयोजन के वे कौन-से नये तरीके ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम में प्रयुक्त किये जाने के लिए उपलब्ध हैं, जोकि अधिकतम रोजगारी के अवसर निर्मित करना सुनिश्चित करते हैं? वर्तमान शताब्दी में, और खास कर द्वितीय महायुद्ध के बाद, वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास की बहुत ही तीव्र गति ने उद्योगों तथा उनकी प्रगति से प्रभावित अन्य गतिविधियों के लिए नयी समस्याएँ पैदा कर दी हैं। ये निर्णय अथवा आयोजन की समस्याएँ हैं, जोकि सगठित प्रक्रियाओं ने अपनी विवादास्पद आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के कारण बड़ी जटिलताओं से पैदा की हैं। इस समस्या का सबसे ज्वलंत उदाहरण है आणविक शक्ति का विकास, जिसका उपयोग मानवता के लाभ के लिए भी किया जा सकता है और विनाश के लिए भी। इन समस्याओं का न तो भौतिक विज्ञान के जरिये ही और न सामाजिक विज्ञान के जरिये ही हल हो सकता है।

हाल के दशकों में माध्यमिक विज्ञानों की अभूतपूर्व प्रगति ने—खास कर सांख्यिकी शाखा ने, जोकि 'सांख्यिकी निर्णय' के नाम से जानी जाती है—भौतिक और समाज विज्ञान की वर्तमान तकनीकों को मिलाने योग्य बनाया है ताकि विवादास्पद समस्याओं का हल हो सके और अनुकूलतम अथवा फलमूलक हल खोजे जा सके। उच्च औद्योगिक उत्पादकता के आर्थिक उद्देश्य और ग्रामीण औद्योगीकरण में बड़ी रोजगारी के सामाजिक उद्देश्य के बीच का मतभेद विवादास्पद समस्या है, जिसका इस तरीके से हल किया जा सकता है। अब तक भौतिक और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच कोई सामान्य दृष्टिकोण नहीं रहा है। यह नया तरीका जिसे वैज्ञानिक 'कार्य-वाहक अनुसंधान' कहा करते हैं, सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसकी सम्भाव्यता आर्थिक, औद्योगिक और

राज्य-वार आधार पर सामाजिक आयोजन में लेकर यानायात नियंत्रण तक है।

ग्रामीण औद्योगीकरण में विवादास्पद पद्धति है—“नियंत्रित परिस्थितियों में स्रोतों का अनुकूलतम बँटवारा।” ग्रामीण औद्योगीकरण में कार्यवाहक अनुसंधान की सम्भाव्यता मुख्य रूप से इसी विवादास्पद पद्धति से सीमित है। अतः प्रयुक्त होनेवाली चुनिन्दा तकनीकों को औद्योगिक आयोजन कहा गया है, जिसमें क्रमबद्ध कार्यक्रम और प्राणवान कार्यक्रम शामिल हैं। औद्योगिक आयोजन की तकनीक परम्परागत ग्रामोद्योगों के विकास अथवा आधुनिक उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में प्रयुक्त कर सकते हैं। उन्हें प्रादेशिक आयोजन में भी, जिनमें परम्परागत अथवा आधुनिक उद्योग और कृषि दोनों ही शामिल हैं, प्रयुक्त किया जा सकता है। विशिष्ट उद्योगों में इसे प्रयुक्त करने का विस्तृत विवरण इस लेख में देना स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

कार्यवाहक अनुसंधान

कार्यवाहक अनुसंधान ही आज एकमात्र उपलब्ध तरीका है जिसे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विज्ञान तथा उसके उत्पादन—तकनालाजी—में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से वैज्ञानिक और अभियंता सक्रिय रूप से ग्रामीण औद्योगीकरण में भाग ले सकते हैं। आयोजन के लिए अनुसंधान शब्दों का प्रयोग विचित्र लग सकता है। अनुसंधान और विकास तथा कार्यवाहक अनुसंधान के बीच भेद यह है कि एक विकास कार्य है और दूसरा मूल्यांकन कार्य। अनुसंधान और विकास कार्य वर्तमान तकनालाजी से अधिक उत्पादकतावाली

नयी तकनालाजी विकसित करने से सम्बन्धित है। कार्यवाहक अनुसंधान वर्तमान और नयी तकनालाजी के मूल्यांकन से सम्बन्धित है, जिससे उनका उपयोग योजित आधार पर पूर्व-निर्धारित आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सके। अनुसंधान और विकास वह अनुसंधान है, जोकि सम्पन्न समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। कार्यवाहक अनुसंधान वह अनुसंधान है जोकि करोड़ों लोगों की प्रगति के लिए परमावश्यक है। तथापि, ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए कार्यवाहक अनुसंधान प्रयुक्त करने में वैज्ञानिकों और अभियंतों की अनुसंधान और विकास से कम आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि हमारे देश में प्राविधिक विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करनेवाली २० से भी अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ हैं, हमारे करोड़ों ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास का मूल्यांकन और उपयोग करनेवाला अब तक वैसा कोई भी सगठन नहीं है। यदि हम औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने की समस्याओं और ग्रामीण औद्योगीकरण के जरिये जन-शक्ति स्रोत के उपयोग की समस्या को एक समान ही समझे, तो इस तरह के सगठन का अर्थ बड़े-बड़े भवनो के निर्माण तथा खर्चीले वैज्ञानिक और अभियांत्रिक उपकरणों से लगाया जा सकता है, जोकि गलत होगा। राष्ट्रीय आयोजन की सबसे बड़ी समस्या को हल करने के लिए इस सगठन में परमावश्यक रूप से ही मेधावी और नेतृत्वशाली वैज्ञानिकों और अभियंताओं का जुटाया जाना शामिल है।

बम्बई - १५ जुलाई १९६३



भारत पर नयी दृष्टि*

गौरी शंकर रायचौधरी

ग्रामीण औद्योगीकरण भारत में एक भारी समस्या है। इस समस्या की विशालता तब स्पष्ट हो जाती है, जब हम भारत की ग्रामीण जन-संख्या की गत्यात्मकता को देखते हैं। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार कुल ४३ करोड़ ९० लाख की जन-संख्या में से ३६ करोड़ आबादी देश के लगभग ६ लाख गाँवों में (साढ़े पाँच लाख से अधिक) है। यह जन-संख्या प्रति वर्ष लगभग २ प्रति शत की दर से बढ़ रही है। और फिर, जैसा कि गत दशक के शहरीकरण की प्रक्रिया से अभिव्यक्त होता है, अब शहरी क्षेत्र में इन ३७ करोड़ ५० लाख व्यक्तियों के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को बसाने की बहुत कम गुंजाइश है। दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि हमें ग्रामीण एवम् शहरी क्षेत्रों में पहले से जो बेरोजगारी है, उसकी समस्या पर अलग-अलग रूप से विचार करना चाहिए।

इस आधार पर ही श्री 'लिण्टन एवम् स्टेपनेक ने 'बड़े शहरों के बाहर औद्योगीकरण' (इण्डस्ट्रियलाइजेशन बियाँण्ड मेट्रोपोलिस) की समस्या पर विचार किया है। बड़े शहरों के बाहर औद्योगीकरण के प्रसार में अनेक बाधाएँ हैं, तथापि यह सुझाव दिया गया है कि दरिद्रता एवम् बेकारी की समस्या को हल करने के लिए हर हालत में भारत को अपने औद्योगिक विकास की गति दुगुनी अथवा तिगुनी करनी पड़ेगी। प्रति वर्ष १५ से २० प्रति शत के मध्य सन् १९५६ को आधार वर्ष मान कर औद्योगिक विकास की औसत दर प्राप्त करने के लिए पूँजी निवेश अर्थात् विनियोजन

बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इस काम के लिए आवश्यक पूँजी की मात्रा के बारे में कुछ अनुमान लगाना हमारे पूँजी उत्पादन अनुपात सम्बन्धी जानकारी पर निर्भर करता है। यह जानकारी कुछ माने में हमारे पूँजी लगाने के क्षेत्र एवम् उत्पादन तकनीक के चुनाव अर्थात् पसन्दगी से हासिल की जा सकती है। इसी पसन्दगी से हमें रोजगारी सम्बन्धी स्थिति की भी जानकारी मिलती है। अत्यधिक पूँजी प्रधान तकनीक के लिए अधिक विनियोजन की आवश्यकता होती है, जबकि उसी अनुपात में रोजगारी में वृद्धि नहीं होती। चूँकि भारत में उत्पादन तथा रोजगारी दोनों का बढ़ाना जरूरी है, इसलिए पुस्तिका के लेखकों ने औद्योगिक विकास की एक नयी नीति अपनाने की आवश्यकता प्रकट की है। इस नीति की प्रमुख विशिष्टताएँ हैं (अ) सम्पूर्ण भारत के बजाय जिले का आयोजन इकाई के रूप में चुनाव, (आ) कौशल प्रधान माध्यमिक प्रविधि (इण्टरमीडियेट टेक्नालॉजी) पर जोर, ओर स्थानीय संस्थाओं के पुनर्गठन के जरिए विकास कार्य में अधिकाधिक रूप से लोक-भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

जिला आयोजन

जिले को आयोजन इकाई के रूप में चुनने के प्रश्न पर केवल किन्हीं विशिष्ट उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से नहीं, बल्कि समग्र योजना में सघन विवेक सयोजन की समस्या के रूप में उसका चुनाव करने की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

*आर पी लिण्टन और जे ई स्टेपनेक • इण्डस्ट्रियलाइजेशन बियाँण्ड दि मेट्रोपोलिस-ए न्यू लुक ऐट इण्डिया, हैदराबाद, १९६३, पृष्ठ ६+४४ (संक्षिप्त संस्करण), मूल्य का उल्लेख नहीं।

अर्थशास्त्र के दर्शनशास्त्रीय सिद्धान्त (क्लासिकल थियरी) की उद्योगों से विकास होता है। यहाँ बदली जा रही है कि उद्योग कार्यक्रम के अनुवर्ती है। यह इसलिए है कि उद्योगों के केन्द्रीभूत होने के फलस्वरूप आर्थिक विकास के तथा कथित विस्तार प्रभाव का बहुत ही सीमित महत्व देखने में आया है। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक केन्द्रीभूत उद्योगोंवाले क्षेत्र के समीपवर्ती भाग के आर्थिक विकास की पद्धति से जाहिर होता है कि वहाँ आय एवम् सम्पत्ति के वितरण में घोर असमानता है। अतः यह सिर्फ किसी जिले के निष्क्रिय साधन स्रोतों का उपयोग करने का ही नहीं, बल्कि यह ठोम तथा सतुलित क्षेत्रीय विकास का श्रीगणेश करने का सवाल है कि हम जिले के एक पार्श्ववर्ती चित्र (डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल) के रूप में शुरुआत करके, उसे जिला योजना में रूपान्तरित करें।

इस चित्र का दूसरा पहलू भी है। अल्प काल में जब तक कि गाँवों में पर्याप्त सामाजिक साधनों (बिजली, सड़क, यातायात आदि) का निर्माण नहीं होता है, देहाती क्षेत्रों में मानाकित सामग्री उत्पादित करने के किसी भी प्रयत्न का फल यह निकलने वाला है कि उत्पादन लागत अधिक होगी। फिर भी लेखकों का मत है कि यद्यपि ऐसे उत्पादनों को अलग से देखने पर लागत अधिक होगी, किन्तु कुल लागत कम होगी, क्योंकि विकास की एक निश्चित सीमा के बाद उन उद्योगों को शहरों से बाह्य लाभ एवम् जीवन की अन्य सहूलियतें अधिक लागत पर प्राप्त होती हैं। यद्यपि अल्प विकसित देशों के सम्बन्ध में यह सत्य है, किन्तु यह सत्य इसलिए नहीं है कि अल्प विकसित देशों में शहर अपनी परिपूर्णता के स्तर पर पहुँच गये हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें शहर प्रायः अनायोजित हैं। इसलिए निकट-भविष्य में हमारे सामने शहरों के पुनरायोजन तथा ग्रामीण विकेन्द्रीकरण के लिए सहायता प्रदान करने में से किसी एक का चुनाव करने की समस्या है, और यह जैसाकि लेखकों का मत है, विभिन्न प्रकार के

उत्पादनों की मार्बजनिक तथा निजी लागत के बीच सम्बन्ध-स्थापित करने हेतु बहुत कुछ परिमाणात्मक अनुसंधान पर निर्भर करता है।

माध्यमिक प्रविधि

रोजगारों के लिए लेखकों ने कौशल प्रधान माध्यमिक प्रविधि के चुनाव का मुद्दा दिया है। यह इस तथ्य से अनुप्राणित है कि भारत न तो इतना बड़ा विनियोजन कर सकता है कि वह पूँजीप्रधान तकनीक के साथ अतिरिक्त श्रम-शक्ति को सम्भाल सके और न वह अपनी औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए परम्परागत तकनीकों पर ही निर्भर रह सकता है। इसलिए माध्यमिक प्रविधि के साथ समझौता किया जाना चाहिए अर्थात् उसका चुनाव किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा समझौता है जो यत्र तथा मूल्य दोनों दृष्टियों से सफल होना चाहिए, किन्तु निश्चय की इस प्रविधि से उत्पादकता इतनी नहीं बढ़ सकती जितनी वह आधुनिक तकनीक में बढ़ सकती है। वैसी अवस्था में विकसित देश माध्यमिक प्रविधि का अनुसरण करने की आवश्यकता महसूस करेंगे। तब प्रश्न उठता है कि माध्यमिक प्रविधि कितनी माध्यमिक होगी, क्या हमारे वित्तीय विनियोजन की सीमाओं के अन्दर रहते हुए एक निश्चित अधिकतम उत्पादकता की गति प्राप्त करने के लिए प्रविधि में सशोधन करना सम्भव हो सकेगा ?

इस सम्बन्ध में बहुत कुछ यात्रिक सभाव्यताओं पर निर्भर करता है। अब यदि कोई इससे एक अल्प कालिक सम्भावना के रूप में स्वीकार भी करे तो भी कोई यह नहीं जानता कि भविष्य में यह क्या रूप धारण करेगी, क्योंकि जब वर्तमान अल्प विकसित देश आज की आधुनिक प्रविधि अपनाने में समर्थ होंगे। तब उन्हें शायद यह जान कर आश्चर्य नहीं होगा कि उस समय के विकसित देशों की प्रविधि की तुलना में उनकी आजवाली प्रविधि पुरानी पड़ेगी। या फिर कोई यह भी बड़ी खुशी के साथ

सोच सकता है कि इतिहास के एक निश्चित स्थल यानी काल में अल्प विकसित देशों की विकास की गति वर्तमान विकसित देशों की विकास की गति से बहुत आगे बढ़ जायेगी। जिससे प्रविधि की दृष्टि से वे विकसित देशों के बराबर होंगे तथा अल्प विकसित देशों की जन-संख्या में कमी होने लगेगी। फलस्वरूप बेकारी की समस्या हल हो जायेगी। अतएव हमें अवश्य ही प्रतीक्षा करके देखना चाहिए।

सलाहकार सहाकरिताएँ

यह सब उसके लिए है कि क्या करना चाहिए, किन्तु एक दूसरा और प्रश्न है कि जो काम करना है वह किया जाना चाहिए? लेखक इन बातों पर जोर देते हैं (अ) प्रत्येक जिले में एक प्रमुख सलाहकार अवश्य ही होना चाहिए और (आ) औद्योगिक सगठनों में सहकारी उद्योग शहरी एवम् ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य विभिन्न प्रकार के संयुक्त उद्योग और कारखानों की शाखाएँ हो सकती हैं। सलाहकार का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें न केवल उच्च तकनीकी योग्यता ही, बल्कि आधुनिक प्रविधि का प्रचार मात्रा में प्रत्यक्ष अनुभव भी होना चाहिए। इन सबसे अधिक बिना दैनंदिन बाह्य सहायता के लिए अपना काम जारी रखने में समर्थ किसी व्यक्ति में कार्य-शक्ति, अभिक्रम और सृजन-शक्ति का होना परमावश्यक है। प्राविधिक सलाह देने से लेकर भावी होनहार उद्योगपतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने तक के विभिन्न प्रकार के काम उक्त सलाहकार करेगा।

यद्यपि हम इस प्रकार के मार्गदर्शक असामान्य व्यक्ति की सेवाएँ प्राप्त कर सकें तो उससे बढ़ कर और कोई बात नहीं होगी। वस्तुतः हम अपनी सामुदायिक विकास योजनाओं में ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता के विचार में एक ऐसे ही सर्वज्ञानी व्यक्ति का स्वरूप रखते हैं, किन्तु हमारे ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता की तुलना में यह सलाहकार अधिक तकनीकी योग्यता

रखेगा और उसे अधिक वेतन भी मिलेगा। हमारा ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता स्पष्टतः इस कार्य में असफल हुआ है, किन्तु यह भी सन्देहास्पद ही है कि उच्च-स्तरीय तकनीकी ज्ञान एवम् उच्च वेतन प्राप्ति के कारण यह सलाहकार सफल हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास केवल एक आर्थिक कार्य ही है—इसमें समाजशास्त्रीय तथा राजनीतिक गुत्थियाँ भी सुलझायी हैं। हमारी नौकरशाही राजनीतिक वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होने के कारण सलाहकार को प्रस्तावित स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकती। दूसरी तरफ अनेक तरह की गुटबन्दियों तथा असमानताओं से वशीभूत जिस तरह का समाज हमारे गाँव में है वह हमारी कोरी आर्थिक उत्प्रेरणाओं से अनुप्राणित, प्रत्युत्तरशील नहीं हो सकता। यहाँ स्पष्ट अभिव्यक्ति की जाय तो यह कहना पड़ेगा कि नौकरशाही की ओर उदासीनता अथवा दबदबे उसके तथा ग्रामीण राजनीति के मध्य हो सकता है कि सलाहकार का कार्य बिल्कुल ही उत्प्रेरक हो। अनेक प्रकार के औद्योगिक सगठन एवम् वित्तीय संस्थाओं के मामले में उनके विकास की ऐतिहासिक परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखना चाहिए।

जनतंत्र में जब तक विरोधी शक्तियाँ अधिक प्रभावशाली स्थिति में हों, तब तक ये संस्थाएँ कदापि विकसित नहीं हो सकती। और जनतंत्र में ही कभी-कभी इन विरोधी शक्तियों का निदान भी बड़ा पेचीदा कर्तव्यमूढ कर देनेवाला बन जाता है। फिर भी, मैं लेखक द्वय के इस मत से पूर्ण सहमत हूँ कि किसी न किसी तरह के सलाहकार एवं विभिन्न प्रकार की आर्थिक संस्थाओं की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में केवल एक बात जोड़ना चाहूँगा कि उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पर्याप्त धानिक तथा राजनीतिक अवस्थाएँ निर्मित करनी चाहिए।

नयी दिल्ली • २४ अगस्त १९६३

स्त्री शिक्षा की समस्याएँ

श्रीपति श्रीदेवी

जबकि स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा उनके स्थान में सुधार होने का, विशेष कर स्वतंत्रता के बाद, स्वागत किया गया है, साथ ही कई समस्याएँ भी खड़ी हो गयी हैं। शिक्षा ने महिलाओं को जो आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, पारिवारिक जीवन, जिममें बच्चों का पालन-पोषण भी शामिल है, के सन्दर्भ में उसके अवाछनीय परिणाम निकल रहे हैं। इससे स्त्री शिक्षा के उद्देश्य, तत्त्व और कार्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हो गयी है।

हाल के वर्षों में भारत ने जिस क्षेत्र में बहुत ही शान-दार प्रगति की है वह है स्त्री शिक्षा। जो भारतीय समाज आज में साठ वर्ष पूर्व तक लड़कियों की शिक्षा को बिल्कुल अनावश्यक समझता था, उसके रुख में आमूल परिवर्तन हो गया है और अब वह उन्हें हर स्तर पर शिक्षा देने की आवश्यकता समझता है। आज स्कूलों और कालेजों में बड़ी संख्या में लड़कियाँ सिर्फ मामान्य शिक्षा और संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षण, नर्सिंग, चिकित्सा, व्यापार, अभियांत्रिकी, कानून, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में काम करने की शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से भी पढ़ने जाती हैं। जिनशक्तियों ने महिलाओं में उच्च शिक्षा का यह विस्तार लाया है, उनके लिए कोई सीधा-साधा कारण नहीं बताया जा सकता। इस विकास में, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए हुए आन्दोलन के परिणामस्वरूप जिन चन्द शक्तिशाली विचारों का प्रसार हुआ, उन्हीं का योगदान है।

महिलाओं के स्थान में परिवर्तन

ये आन्दोलन दो बाहरी तथ्यों के चुनौतीपूर्ण प्रत्युत्तर स्वरूप थे—भारत में अंग्रेजी राज का आरम्भ और इसाई धर्म के प्रचारार्थ इसाई मिशनरियों का आगमन। साम्राज्यवादी प्रवृत्तिवाले अंग्रेजी प्रशासन का प्रारम्भिक इसाई मिशनरियों की धर्मपरिवर्तन नीति के साथ-साथ कड़ा विरोध किया गया। राष्ट्रवादी

आन्दोलन, विशेषकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कि महिलाओं की स्थिति सुधारने में गहरी दिलचस्पी रखते थे, इतना शक्तिशाली था कि महिलाओं को अपनी उन्नति के लिए स्वयं ही आगे बढ़ कर काम करने का प्रोत्साहन मिला। इससे स्त्री आन्दोलन का आरम्भ यद्यपि कुछ देर से ही हुआ, परन्तु उसने निरंतर महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए आन्दोलन किया। फिर रामकृष्ण मिशन और ब्रह्मवाद आन्दोलन का आरम्भ हुआ, जिसने अपने साधारण कार्यक्रम में महिलाओं के निस्तार को भी शामिल किया। फलतः क्रियाशीलताएँ बहुत अधिक हो गयी, जिससे अचानक ही महिलाओं की स्थिति में बहुत ही अनुकूल परिवर्तन और अतन्त निस्तार हुआ।

स्वतंत्रता मिलने के बाद पिछले पन्द्रह वर्षों में महिलाओं के निस्तार के साथ-साथ सम्पत्ति और तलाक अधिकारों तथा पुरुषों से बराबरी का हक आदि जैसे अन्य अधिकारों से एक शक्तिमय क्रांति हुई है, जिससे विभिन्न वर्गों की महिलाओं में बहुत भारी परिवर्तन हुए हैं। उच्च वर्गों में, जो कि आबादी का सबसे कम प्रतिशत है, स्त्री शिक्षा अधिकतर 'सजावट की वस्तु' ही रही है, यद्यपि इन वर्गों की कई महिलाओं ने अपने को सार्वजनिक कार्यों में भी लगा दिया है। मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गों में शिक्षा और स्वतंत्रता ने कई परिवर्तन लाये हैं, जिनमें से कुछ लाभदायक हैं, जबकि बाकी पारिवारिक सुख

की राह में बाधक बन रहे हैं।

सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह है कि विवाहित और अविवाहित शिक्षित लड़कियाँ बहुत बड़ी संख्या में रोजगारी में लगी हैं। आरम्भ में तो सिर्फ अविवाहिताएँ ही नौकरी किया करती थी और वह भी अध्यापन तथा चिकित्सा क्षेत्रों में ही, क्योंकि उस समय उनके लिए और कोई मार्ग नहीं था, परन्तु आज स्थिति बदल गयी है और करीब-करीब हर क्षेत्र में महिलाएँ कार्य कर रही हैं तथा अन्य महिलाओं की प्रेरणा और अपने परिवार की अवस्था पर ध्यान दिये बिना कार्य करने के लिए आकर्षित हो रही हैं। श्रमिकों की माग बढ़ने से, विशेष कर पंच वर्षीय योजनाएँ आरम्भ होने के बाद—जिनसे हर क्षेत्र में रोजगारी की सम्भाव्यताएँ और बढ़ गयी हैं—काफी संख्या में महिलाएँ पूर्ण अथवा अर्ध-कालीन कार्यों में लगी हैं। इससे निश्चय ही महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, जिसके फल-स्वरूप विवाह के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन हुए हैं और माता-पिता को दहेज में होनेवाले भारी खर्च की चिंता से मुक्ति मिली है। दहेज के सम्बन्ध में हाल ही में बने कानून से भी स्थिति में सुधार हुआ है।

आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं के लिए विवाह अब आर्थिक आवश्यकता नहीं रही, बल्कि पसन्द की बात हो गयी है। इसने सकीर्ण सामाजिक दृष्टिकोण की सीमा तोड़ दी है और अन्तर्जातीय तथा अन्तर्साम्प्रदायी विवाह हो रहे हैं। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग की सभी शिक्षित लड़कियाँ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। कुछ युवक अभी भी चुपके-चुपके दहेज मागते हैं। अतः कुछ नौकरीपेशा लड़कियाँ अविवाहित रहने को मजबूर हैं, यद्यपि हमारे समाज-सुधारक और सरकार इस प्राचीन प्रथा को समाप्त करने के लिए जोरदार प्रयास कर रही हैं। फिर अधिक उम्र होने पर भी विवाह होते हैं, जिसमें लड़कियाँ जानबूझ कर अथवा अनजाने

विवाहित पुरुषों से, जिनकी पत्नी है अथवा मर चुकी है, ब्याह कर लेती हैं। नये हिन्दू विवाह अधिनियम में इस बहु-विवाह से महिलाओं की रक्षा की गयी है।

पारिवारिक जीवन को खतरा

तथापि महिलाओं के निस्तार को पारिवारिक सम्बन्ध भग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यद्यपि इसके लिए अनेक बड़े कारण हैं, युवा शिक्षित विवाहित जोड़ों का अपना घर खुद बसाने की इच्छा एक मुख्य कारण मानी जाती है। प्राचीन पारिवारिक सांस्कृतिक पद्धति नष्ट हो गयी है और इसके साथ ही संयुक्त परिवार के विभिन्न लाभ भी। फिर, यह भी कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति, जिसमें पश्चिमी विचारों के अवशेष अभी भी वर्तमान हैं, ने हमारी महिलाओं को पश्चिमी दृष्टिकोण दिया है, जिससे कि वे व्यक्तिवादी हो गयी हैं, जोकि हमारे लिए बिल्कुल विदेशी है। दोषारोपण किया जाता है कि इस नयी बात से पुराने किस्म के परिवार भग होते जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षित लड़कियाँ कृत्रिम बनती जा रही हैं और वे अब अपने देश अथवा परिवार की सामाजिक और धार्मिक परम्पराओं में रुचि नहीं रखती। वे अब बड़ी रूमानी समझी जाती हैं, जोकि उपयोगी घरेलू कार्य पर ध्यान देने के बजाय सस्ती और गदी फिल्मों तथा अन्य उत्तेजक कार्यों से अधिक प्रभावित हैं। अतः परिवार का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन खतरे में बताया जाता है। कुछ हद तक यह सही हो सकता है, परन्तु यह भी स्वीकार करना होगा कि आधुनिक युवती दो सप्ताह के बीच फँसी है—समाप्त हो रही पुरानी दुनिया और नवजात सप्ताह। निश्चय ही वह इस स्थिति में अपने को व्यवस्थित कर रही है। प्रायः वह पारिवारिक जीवन और अपने धर्म के बीच उलझ जाती है। जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास में उसकी मानसिक और भौतिक दोनों ही रूपों में अपरिमित हानि हो रही है। कुछ लोग इन अवस्थाओं में बहुत चिन्तित

है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जोकि उत्तम सन्तति और उत्तम विश्व के लिए महिलाओं की शिक्षा को परमावश्यक मानते हैं। ये दोनों ही वर्ग दो भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों ही के अपने-अपने समर्थक हैं।

बच्चों का पालन-पोषण

एक वर्ग के निराशावादी दावे पर ध्यान देते हुए यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि क्या इतना दुखदायी विकास हुआ है। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि स्नातक पत्नियों ने, जोकि कहीं काम करती हैं, बच्चा के पालन-पोषण तथा पूर्णकालीन धंधे के अनुगमन को समाहित करने की समस्या खड़ी कर दी है, क्योंकि बच्चों पर पूरा-पूरा ध्यान दिये जाने की जरूरत है। डाक्टरों ने यह पाया है कि जिन बच्चों को सविराम दूसरों की देखभाल में छोड़ दिया गया है उन्हें अधिजठर व्रण, फीलपाव तथा अन्य बीमारियाँ हो गयी हैं। अतः बच्चों को माँ-बाप के प्यार अथवा देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

साथ ही मनोवैज्ञानिक यह बताते हैं कि बहुत अधिक आरक्षण भी नहीं देना चाहिए, जैसे बच्चों को अपनी आवश्यकताएँ नहीं बढ़ाने दी जाती। उन्हें कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। बच्चों पर माँ का प्रभुत्व कभी भी उनके (बच्चों) लिए लाभदायक नहीं हो सकता। अल्वा मिरडल और बायला क्लेन अप्प्ली पुस्तक 'वीमेन्स टू रोल्स' में कहती हैं - "अधिक दबाव अथवा अधिक प्यार करने से बच्चों की शिक्षा की दिशा अनिश्चित हो जाती है। माता-पिता के लिए सम्भवतः सबसे अच्छा यह है कि वे अधिक ध्यान न दे, नहीं तो स्वचेतना से उनका स्वाभाविक विश्वास समाप्त हो जायगा। चूँकि माता-पिता के पालन-पोषण में यह बहु-विशेष अवस्था वर्तमान रहती है कि उत्पादन उत्पादक के साथ-साथ उत्पादन की प्रक्रिया को भी आक सकता है, अतः पूर्णता का लक्ष्य रखना बेकार है। जहाँ बच्चे मनोवैज्ञानिक साहित्य पढ़ने लायक हो गये, वे अपने माता-पिता

को किसी न किसी अपराध के लिए कोसना शुरू कर देंगे।"

भविष्य की सम्भावना

दूसरे वर्ग का विचार कि उत्तम सन्तति तथा उत्तम विश्व के लिए महिलाओं की शिक्षा परमावश्यक है, सही है तथा होना चाहिए, क्योंकि सारा शैक्षणिक प्रशिक्षण बेकार नहीं जायगा। माँ के रूप में महिलाओं को महत्वपूर्ण कार्य करना है। उनके लिए शिक्षा पुरुषों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन पर परिवार के अपने पालन-पोषण तथा अपने बच्चों को, जोकि भावी नागरिक हैं, अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जोकि उन्हें घर तथा समाज में अच्छी तरह कार्य करने में मदद दे। जब भारत अमेरिका और इंग्लैंड की तरह उच्चतम औद्योगिक राष्ट्र हो जायगा तो महिलाएँ घर और दफ्तर दोनों का ही काम बिना विशेष कठिनाई के सम्भाल सकेंगी, क्योंकि कई नयी और मुबरी घरेलू सुविधाएँ मिल जायेंगी जो कि उनके समय और शक्ति की बचत करेगी। इस सन्दर्भ में जॉन डी डुरैण्ड की सुखद घोषणा का जिक्र करना दिलचस्प होगा, जिन्होंने अपने लेख 'मैरिड वीमेन इन दि लेबर फोर्स' में कहा है कि नित नयी चीजों के आविष्कार होते जाने से एक दिन ऐसा आयगा जब किसी घर में कोई काम नहीं होगा और गृहणियाँ आबादी की कार्यकारी वर्ग नहीं रह जायेंगी। फिर, परिवार नियोजन के प्रचलित होने से काम और भी कम हो जायेगा।

माँ का प्रभाव

फिर भी, समस्या वही रह जाती है, क्योंकि घर और बच्चे नजरअदाज होने ही वाले हैं और यदि बच्चों को अच्छी तरह बढना है तो उन्हें माता की अच्छी देख-भाल चाहिए ही—खास कर शिक्षित माँ की—क्योंकि पुरुषों और नारियों की सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का निर्णय प्रारम्भिक वर्षों में ही

माँ के ससर्ग में होता है। जैसा कि डा. राधाकृष्णन् कहते हैं—“इसलिए यदि माँ शिक्षित और नव-विचारों का स्वागत करनेवाली, जिज्ञासु और सचेत, अफवाहों और परम्परा पर ध्यान न देकर तथ्य पर ध्यान देनेवाली, अपने आसपास की दुनिया के मूल्य की जानकार और उसमें दिलचस्पी रखनेवाली, इतिहास और साहित्य में रूचि रखने तथा आनन्द लेनेवाली हो तो उसके बच्चे ये चीजें उससे सीखेंगे। शिक्षित सजग माँ, जोकि अपने घर में अपने बच्चों के बीच रह कर काम करती है, चरित्र और बौद्धिक ज्ञान की विश्व में सबसे बड़ी शिक्षिका है। ऐसे घरवाले समाज के बच्चे जब स्कूल जाना आरम्भ करते हैं तो उन्हें सब चीजों की जानकारी और समझ-बूझ रहती है तथा वे सुसंस्कृत होते हैं, जिससे उन्हें स्कूल का अधिक लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा जितना कि सम्भव नहीं होता।”

यात्रीकरण के प्रभाव

लेकिन सबसे विकट प्रश्न है कि श्रम बचानेवाली खोजों के उपयोग से अवकाश के जिन बड़े क्षणों की प्राप्ति होगी, क्या उसे महिलाओं को अपनी अमेरिकी बहनों की तरह उकताहट से बचाने अथवा अधिक पैसे कमाने के लिए बेचने होंगे? यदि वे ऐसा करती हैं तो बच्चों के सही पालन-पोषण की जिम्मेदारी स्कूलों की हो जायेगी। अमेरिकी स्कूल इस दोमुखी कार्य के उपयुक्त नयी कार्य-विधि आरम्भ करने हेतु गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। सम्भवतः इन्हीं परिणामों की कल्पना करते हुए महात्मा गांधी बड़े पैमाने के यात्रीकरण से भय खाते थे। हमारा भविष्य देश में किस हद तक औद्योगीकरण होता है और कहाँ तक महिलाएँ इस यात्रीकरण को अपने घरों में प्रवेश करने से बचा पाती हैं, इस पर निर्भर करता है।

माना कि काफी अवकाशवाली शिक्षित महिलाएँ अपने घर में रह कर घर और बच्चों की देख-रेख पर पूरा ध्यान देने का निर्णय करती हैं, फिर भी यदि उकताने का नहीं तो निराश होने का खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि उनकी शिक्षा के उपयोग का मार्ग नहीं रहेगा।

उनकी शिक्षा निरर्थक जायेगी और वे शिक्षा में दिलचस्पी लेना कम कर देंगी और काफी समय बाद महिलाएँ फिर से उतनी ही अज्ञानी हो जायेगी जितनी कि सौ साल पहले थी। अतः महिलाओं को अपने घरेलू कार्य के अलावा कुछ काम करना ही चाहिए। यह काम दो-तीन घंटे रोजाना का हो सकता है, जिससे वे अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शीघ्र घर लौट सकें। यदि सभी शिक्षित महिलाओं को इस तरह का आशिक काम दे दिया गया तो वे कम महत्वपूर्ण कार्यों से बंध जायेगी जहाँ कि उन्हें मानसिक कार्य नहीं करना होगा। यदि इसके विपरीत महिलाएँ प्रमुख प्रशासनाधिकारी अथवा डाक्टर अथवा वकील बनाना चाहती हैं तो उन्हें धंधे के लिए तैयार किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें मानसिक सतोष मिलेगा तथा पूर्णता का भान होगा। लेकिन यह फिर से हमें प्रारम्भिक प्रश्न पर ले जाता है।

विशेष पाठ-चर्या

इस दूषित वृत्त से निकलने हेतु रामबाण के रूप में महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा का सुझाव दिया गया है। इस प्रश्न पर तरह-तरह के विचार प्रकट किये गये हैं। विवाद महिलाओं के लिए विशेष विषयों के मूल्य पर है—क्या लड़कियों की सीमित शारीरिक क्षमता को देखते हुए अध्ययन क्षेत्र सीमित कर दिया जाय अथवा उनके लिए बिल्कुल ही अलग पाठ्यक्रम बनाया जाय जिसमें गृह विज्ञान और संबंधित विषय हों। लड़कियों के लिए बिल्कुल ही अलग पाठ्यक्रम से कई खतरे हैं। उनका ज्ञान घरेलू कार्य तक सीमित हो जायेगा और उससे भारत में महिलाओं की प्रगति रुक जायेगी। व्यवहारतः यह स्त्री शिक्षा के लिए घक्का सिद्ध होगा। महिलाओं की शिक्षा का क्षेत्र सीमित कर राष्ट्र अपने आधे जन-स्रोत को खो देगा।

यह तर्क लड़कियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम लागू करने के विपक्ष में नहीं दिया गया है। निश्चय ही विशेष पाठ्यक्रम हो सकते हैं, बशर्ते कि अन्य विषयों

के अध्ययन पर रोक न हो। फिर, विशेष शिक्षा लेने-वाली महिलाएँ, अपने को अपने घरों तक सीमित रखने में कभी भी सफल नहीं हो सकती। निस्तार और पुरुषों से बराबरी का हक औरत को घर के बाहर भी कुछ रुचि पैदा करेगा। चूँकि बच्चों का पालन-पोषण औरत की जिम्मेदारी है, अतः उन्हें घर में हमेशा काम मिलेगा। जैसा कि मिस डेटन पोलक कहती हैं, “समानता की ओर बहुत अधिक प्रगति होने के बावजूद, महिलाओं के लिए जीवन पुरुषों में अधिक कठिन है और सम्भवतः रहेगा।” उसे इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आयोजन करना होगा और तदनुसार अपने को व्यवस्थित करना होगा। इसी संकट का सामना करते हुए इंग्लैंड में आबादी सम्बन्धी रायल कमीशन ने यह विचार प्रकट किया कि “महिलाएँ राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में जो योगदान

दे रही हैं, उसे सीमित करने की कोशिश करना महिलाओं के लिए सर्वांगीण हानिकार होगा। यह सत्य है कि मातृत्व और पूर्ण-कालीन पेशे के बीच सही संघर्ष है। इस संघर्ष का एक अंश महिलाओं के जैविक कार्य में अन्तर्निहित है, परन्तु एक अंश कृत्रिम है और इस कृत्रिम तत्व की निरन्तर उपस्थिति मातृत्व के स्थान को निकृष्ट विकल्प में—बाहरी रोजगारी अथवा सार्वजनिक जीवन में—गिराने का प्रयास करती है। अतः हम शिक्षण और असैनिक सेवाओं में रोजगारी पर से विवाह प्रतिबन्ध हटाने का स्वागत करते हैं और यह समझते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था खोज निकालने का समझ-बूझ कर प्रयत्न करना चाहिए कि महिलाओं के लिए मातृत्व और घरेलू कार्य को बाहरी गतिविधियों के साथ मिलाना सहज हो सके।”

हैदराबाद. ५ अगस्त १९६३

इसीलिए राज्य के आदेश ही अंतिम आदेश नहीं होते। हमारे आचरण का मार्ग-दर्शन सत्ता की आवाज से नहीं होता। सत्ता के परिणाम तो सिर्फ आदर्श अधिकारों की पूर्ति ही कर सकते हैं। जनता से राज्य भक्ति की अपेक्षा करने के पहले, न्याय का तकाजा है कि राज्य मनुष्य को मनुष्य की हैसियत से उसका सब कुछ दे। व्यापक तौर पर, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे युग में जबकि सक्रिय नागरिकता वयस्क व्यक्तियों को प्राप्त हो, तब तो राज्यों की कर्तव्य-परीक्षा पूर्व समय की अपेक्षा और भी गंभीर हो जाती है। जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता आ जाती है वे देर-सबेर सत्ता के परिणाम अधिकारों में देखने का आग्रह करने लगते हैं। वे ऐसी संस्थाओं का निर्माण करेंगे जिनके जरिये अधिकारों की सुगमता से प्राप्ति की जा सके। वे सुविधाओं को व्यापक रूप दे देंगे या उसे रद्द कर देंगे। वे यह भी आग्रह करेंगे कि स्वतंत्रता और समानता, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य स्वाभाविक परिणाम हैं। वे अपने उन भाव-विचारों का प्रसारण समाज के पूरे ताने-बाने में करेंगे, कम से कम उस सीमा तक जहाँ राज्य की सत्ता अधिकाधिक स्पष्टता के साथ सबकी मर्जी पर निर्भर करती है। अंत में, इन लोगों का अवरोध कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसा कि एकटन ने बताया है, जनता के पास गुप्त अधिकार होते हैं जिससे निपटने की शक्ति या एकता बहुत थोड़े अल्प मत के पास होती है। इसलिए राज्य को, अगर वह जीवित रहना चाहता है तो जनता की मांग के सामने बदलना पड़ेगा; क्योंकि सार्वजनिक कल्याण पर उसका भी समान दावा होता है और उसकी अभिवृद्धि उसका उद्देश्य होता है।

हैरोल्ड जे. लास्की . ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स

बंगाल में शहरीकरण के कुछ पहलू

मीरा गुहा

अंग्रेजी शासन के आगमन से भारत के अन्य स्थानों के समान बंगाल की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को भी बुरी तरह आघात पहुँचा। कृषि व्यापार की वस्तु बन गयी और कारीगर तथा व्यापारी अपने जीविकोपार्जन के पुद्गैनी धंधों से वंचित हो गये। ग्रामीण आबादी का नये औद्योगिक केन्द्रों में स्थानांतरण हुआ और उसने जीवन-यापन के लिए नये-नये काम-धंधे अपनाये। शहरीकरण की इस प्रक्रिया से मानवीय सम्बन्धों में भी परिवर्तन आये।

बंगाल में शहरीकरण की प्रक्रिया में सन्निहित परिवर्तन ग्रामीण स्वायत्तता अथवा आत्म-निर्भरता पर लादे गये हैं। इस ग्रामीण आधार के अन्दर एक पेशेवर परम्परावलम्बन है, जिसका उद्देश्य है स्वावलम्बन। फलतः स्वरूप या पद्धति उस चुनरी के समान है, जिसमें कृषक समुदायों रूपी 'बिन्दियों' के छोटे-छोटे 'गुच्छ' और उनके साथ विशिष्ट कुटीरोद्योगों में लगे कारीगरों रूपी 'बिन्दियों' के बड़े-बड़े 'गुच्छ' हैं। स्थान-विषयक दृष्टि से इसमें ऐसे गाँव आते हैं, जिनमें एक या अधिक प्रकार के काम-धंधे चलते हैं और जो 'साप्ताहिक बाजारों' अथवा 'मौसमी मेलों' के माध्यम से दस्तकारी केन्द्रों से जुड़े हुए होते हैं। 'साप्ताहिक बाजारों' से पास-पड़ोस के कुछ गाँवों का सम्पर्क होता है, जबकि 'मेलों' का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। इस प्रकार के मेले प्रायः धार्मिक पर्वों के वक्त लगते हैं, किन्तु आस-पास के अनेक जिलों के आदान-प्रदान केन्द्र के रूप में आर्थिक दृष्टि से वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

प्राचीन अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन

इस प्रकार की जीवन पद्धति में कई तरह से परिवर्तन आये हैं, किन्तु इनका ठोस रूप से अध्ययन करने से पूर्व इनमें सन्निहित कुछ अधिक गहरे पहलुओं का अध्ययन करना बेहतर होगा। अर्थ-

व्यवस्था में परिवर्तन मुख्य पृष्ठभूमि है और ऐतिहासिक दृष्टि से यह पिछले दो सौ वर्ष से भारत-वर्तानिधा आर्थिक सम्बन्धों से जुड़ी हुई है।

अंग्रेजों ने १७५७ तक अन्य यूरोपीय प्रतियोगियों को बाजार से समाप्त कर दिया था। अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार कर उन्होंने देश के व्यापार में एकाधिकार जमा लिया था। इस प्रक्रिया के प्रथम सोपान में उन्होंने कृषि को एक व्यावसायिक वस्तु बनाया और रेगम, इण्डिगो तथा अन्य इस प्रकार की वस्तुओं की खेती अंग्रेजों के एकाधिकार की चीज बन गयी। यहाँ यह बड़े मजे की बात है कि इस नये व्यवसाय ने भारतीय पूँजी को भी आकर्षित किया, जिसने क्वचित् रूप से अंग्रेजों की पूँजी के साथ गठ-बधन किया। तथापि, बाद में अंग्रेजी व्यापार और उद्योग की संरक्षण-नीति ने इन भारतीय व्यापारियों को विस्थापित कर दिया तथा उन्हें इसके बदले स्थायी बन्दोबस्त (परमानेंट सेटलमेण्ट) द्वारा भूमि-प्रलोभन दिया गया। इस संरक्षण नीति ने दस्तकारी उद्योगों पर भी कुठाराघात किया और कारीगर अपने परम्परागत काम-धंधों से वंचित कर दिये गये। प्राचीन भारतीय अर्थ-व्यवस्था बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गयी। नयी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन केन्द्रों के अभिनवीकरण को वाष्प उत्कर्षण के समारम्भ द्वारा अन्तिम उत्प्रेरणा प्रदान की गयी। इन

नये केन्द्रों में विस्थापित हो कर आयी आबादी ने उसके समक्ष जो विविध अवसर प्रस्तुत हुए, उनमें चुनाव प्रवृत्ति का परिचय दिया। बोलपुर-रायपुर-इलमबाजार क्षेत्र इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त उदाहरण है।

बोलपुर-रायपुर-इलमबाजार

यह क्षेत्र अजय नदी के उत्तरी किनारे—जोकि बीर-भूम जिले की सीमा है—के साथ-साथ फैला हुआ है। कभी इस मरिता तट पर मुपुर, रायपुर तथा इलमबाजार जैसे व्यावसायिक केन्द्र थे। इस नदी का महत्व इसलिए था कि यह गंगा के किनारे पर कतवा की ओर जाने के लिए एक माध्यम के रूप में थी। इस क्षेत्र की दिवानी १७६५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दी गयी, और अंग्रेजों की व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू हुईं तथा रेशम उद्योग में उनका एकाधिकार था—उसमें ४५ से ६५ लाख तक रुपये उनके लगे थे। एक अंग्रेज अभिकर्ता जॉन चीप (John Cheap) ने 'इण्डिगो' की खेती प्रारम्भ की और मुहल तथा मुपुर में इण्डिगो के कारखाने खोले गये।

रायपुर के एक सम्पन्न बंगाली कायस्थ श्याम किशोर सिन्हा ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अभिकर्ता के रूप में काम किया और उसने यूरोप को निर्यात करने के लिए जॉन चीप को वस्त्रों की पूर्ति की। रायपुर के समीप इण्डिगो के कारखाने में श्याम किशोर के पौत्र सितीकान्त भी हेनरी एसकिन (Eiskine) के साथ भागीदार हुए। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ अपने भाग्य का तादात्म्य स्थापित कर उक्त परिवार ने बहुत धन कमाया और शीघ्र ही जमींदार परिवार बन बैठा। सितीकान्त के बच्चे शिक्षा-प्राप्ति के लिए इंग्लैंड भेजे गये। उनमें से एक वकील बना और 'पीर' की पदवी पानेवाला वह प्रथम भारतीय था। तदुपरान्त परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और

कलकत्ता में विभिन्न उद्योग-वधों में अच्छे पद प्राप्त किये।^१

तथापि, जर्मनी में मस्ती लागत पर उत्पादित सॉल्लिण्ट रजको की स्पर्धा में 'इण्डिगो' उद्योग की अवतति हो गयी। फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक सभी कारखाने बन्द कर दिये गये—तत्कालीन फलते-फूलते मुहल तथा मुपुर के केन्द्रों के बुरे दिन आ गये। इसी वक्त एक अन्य कारक का प्रादुर्भाव हुआ जिनमें शहरी केन्द्रों की स्थापना में और कुछ परिवर्तन लाने में अपना प्रभाव डाला। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने १८५५ में बंगाल को उत्तरी भारत में मिलाते हुए अपेक्षाकृत एक लघु रेल मार्ग का निर्माण किया। अजय नदी पर से होकर यह रेलवे लाइन उत्तर दक्षिण रूप में गयी थी।

द्रुत विकास

बीरभूम जिला सदैव ही एक अच्छा अतिरिक्त चावल उत्पादक क्षेत्र रहा है। प्रथम महायुद्ध के समय जब चावल की कीमतें बढ़ी तो चावल कुटाई वहाँ का एक लाभदायक उद्योग बन गया। रेलवे लाइन के आम-पाम गुशकारा, बोलपुर, अहमदपुर और सथिया जैसे नये चावल कुटाई केन्द्र खुले। मुपुर से छ मील की दूरी पर स्थित पुराना इण्डिगो केन्द्र बोलपुर उस वक्त एक मामूली छोटा सा गाँव था, जो आज तब से विकसित होते-होते क्षेत्र का एक सर्व प्रमुख चावल व्यापार केन्द्र बन गया है। शहर में अब काफी श्रमिक आबादी है और मौसमी काल में बोआई व कटाई का काम करनेवाले सथाल आकर देहाती वातावरण निर्मित कर देते हैं। पचास वर्ष की अवधि में स्वयम् बोलपुर का बड़ी द्रुत गति से विकास हुआ है—सन् १९०१ में उसकी आबादी ३,८३१ थी और १९५१ में १४,८०२। इलम-

* निर्मल कुमार बोस मॉडर्न बंगाल; १९५०, पृष्ठ २०-२३.

बाजार जानेवाली सड़क के समीप एक छोटे-से पुरवे से शुरू होकर इसका क्षेत्र उत्तर की ओर बन्दगोरा और त्रिगुलीपट्टी तक फैल गया है, जो आज इसकी नगर-पालिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

अद्रा-रघुनाथपुर §

अब हम उस क्षेत्र के जीवन मार्ग में रेलवे शहर के विकास से हुए परिवर्तनों का उदाहरण ले, जो प्रधान रूप से ग्रामीण यानी देहाती क्षेत्र था। रघुनाथपुर मानभूम जिले में एक बहुत ही प्राचीन गाँव है। यह गाँव पंचेत के राजा का हेड क्वार्टर था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बगाल से जानेवाले गया-बनारस मार्ग पर एक छोटी-सी चट्टी या डाकघर प्रतीत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु (१४८५-१५३३) ने जब गया की पैदल तीर्थयात्रा की तो यही मार्ग अपनाया था। रघुनाथपुर के दक्षिण और पूर्व में अन्य कई पुराने गाँव हैं। पूर्व की ओर मौजा आरा के चार गाँवों में विष्णुपुर नमूने के अनेक इंटों से बने मन्दिर हैं और वे बाकुरा तथा बर्दवान जानेवाले मार्ग पर अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में प्रारम्भिक जन-संख्या इस प्रकार थी पंचेत के राजा ने माल उगाहने और पुजारियों के रूप में काम करने के लिए कनौज (उत्तर प्रदेश) से बुला कर पाँच ब्राह्मण परिवार बसाये। उसने मौजा आरा में उन्हें जमीन दी। आज वहाँ के ब्राह्मण परिवार अपने को उन्हीं के वंशज कहते हैं। वहाँ की आदिवासी जाति बोरी थी, जो राजा की पालकी इधर-उधर लाया-ले जाया करती थी। इसके अलावा लुहार, कुम्हार, मछुवे, बढई तथा तेली भी थे, जो अपना-अपना पेशा किया करते थे।

§ इस क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी कलकत्ता विश्व विद्यालय के भूगोल विभाग से सम्बद्ध कुमारी सीखा चक्रवर्ती ने इकट्ठी की है।

आस-पास के क्षेत्र और रघुनाथपुर के जयचण्डी पहाड़ में भी अयरक (ओरे) मिलने के कारण क्षेत्र का आर्थिक उपयोग करने की दिशा में एक नयी सम्भाव्यता सामने आयी। भविष्य में इन कच्चे मालों का औद्योगिक उपयोग करने की दृष्टि से सिधभूम के अयस्क उत्पादक क्षेत्र को रानीगञ्ज और बैराकड की कोयले की खानों से जोड़ने के लिए क्षेत्र से हो कर एक रेलवे लाइन निकाली गयी। काशीपुर तथा आरा मौजों के बीच अद्रा नामक एक नया रेलवे शहर बसा और इसने जनता के जीविकोपार्जन की पद्धति में एक सामान्य परिवर्तन ला दिया है।

रोजगारी की पद्धति

रेलवे के कारखाने (रेलवे सेटलमेण्ट) काशीपुर और आरा के दो छोटे-छोटे टोलो-मलासखोला और पाचूडागा-नक फैल गये हैं। रेलवे की वर्कशाप में रोजगारी मिलने के कारण, इस नये शहर ने पास-पड़ोस की जन-संख्या आकर्षित की है। कृषि कार्य काफी कम हो गया है तथा उसी प्रकार पुराने पुश्तैनी धवे भी। 'बोरियो' को या तो कुली कार्य में अथवा रेलवे के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का काम मिलता है। जमींदारी उन्मूलन के साथ ब्राह्मणों की बहुत-सी जमीन चली गयी और अब वे या तो रेलवे कार्यालय में कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं अथवा झरिया में कोयले की खानों में क्लर्कों का। लुहारों और बढइयों ने अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ दिया है। अब लुहार रेलवे में 'फीटरो' और 'वेल्डरो' का काम करते हैं तथा बढई रेलवे की 'वर्कशाप' में बढइयों का। इसी प्रकार तेलकार भी रेलवे में काम करने लगे हैं और आसनमोल तथा रानीगञ्ज से आ कर मारवाडी व्यापारी वाणिज्य-व्यवसाय के क्षेत्र में घुस गये हैं। इस तरह जाति के आवार पर चलनेवाले पुश्तैनी काम-धंधों में एक प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। यद्यपि कुछ आवादी-बहुत ही कम-अब भी खेती करती हैं, पर प्रत्येक परिवार

के लगभग ७५ प्रति शत व्यक्ति रेलवे अथवा खानों में मजदूरी करते हैं।

रिसड़ा

तीसरा उदाहरण है हुगली के दोनों किनारों पर घनी आबादीवाले चिरतन गहरीकरण में विशुद्ध औद्योगिक इकाई का। बिप्रदास १४६५ में लिखित अपनी रचना मनसा मगल में हुगली के दोनों किनारों पर बसे गावों का वर्णन करते हैं। त्रिवेणी से नीचे की ओर सप्तग्राम, कुमारहट्ट (हाली शहर), हुगली, भटपाड़ा, बोरो (एक बस्ती जो अब चन्द्र नगर के क्षेत्र में आती है), काकीनारा, मूलजोडे, गुरुलिया, तेलिनीपाड़ा, भद्रेश्वर, चम्पादानी, इचापुर, डिगा (वैद्यवती खाल), रामनान, अकनाख, महेश, रिसड़ा, कोन्नागर, कोटरग, चाणक, मुकुचर, काम-राहटी, अडियादह, घुसुरी और चित्तपुर का वर्णन है। चित्तपुर का सर्व मगल देवी के मन्दिर के साथ वर्णन किया गया है। नदी के इस किनारे के साथ-साथ ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यावसायिक हित १८वीं शताब्दी में कलकत्ता—जॉब चारनोक (Job Charnock) द्वारा बसाये गये सूतानट्टी, गोविन्दपुर और कालीकाता क्षेत्र—में घनीभूत हो गये थे। नदी के किनारों के देहाती वातावरण में अवस्थित इन गावों में या तो ब्राह्मणों के पठन-पाठन केन्द्र थे या छोटे-छोटे बाजार व व्यापारिक बस्तियाँ थी अथवा बुनाई केन्द्र। इस अवस्था पर द्रुत गति से हुए औद्योगिक विकास का बहुत प्रभाव पड़ा।

जूट मिलों की स्थापना

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक आते-आते थोक रूप में सामान के आदान-प्रदान सम्बन्धी व्यापार में जूट का महत्व सामने आ चुका था। इसकी फसल पर बगाल का एकाधिकार है, इसलिए नदी-किनारों पर जूट मिलों की स्थापना स्वाभाविक थी। प्रथम

मिल १८५५ में रिसड़ा नामक स्थान पर स्थापित हुई थी—१९४० तक दनकी सख्या १०१ तक पहुँच गयी थी। रिसड़ा का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से शहरी विकास की प्रक्रिया का अधिक स्पष्ट चित्र सामने आ सकेगा।

गाँव के रूप में रिसड़ा को महेश के समीप होने का लाभ प्राप्त था, जोकि 'रथयात्रा पर्व' के लिए सुप्रसिद्ध है। रिसड़ा स्वयम् पान के बागानों के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान शहर के पुराने घरों—बार्ड तीन व चार—में बहुत तग गलियाँ—मात्र ढाई गज चौड़ी—थी। उसके अन्दर तीन जाति-प्रधान मुहले हैं—बर्न्डीपाड़ा में बोरी है, जोकि परम्परा से पान की खेती करते हैं, ठेकीपाड़ा में ठेकी है, वे भी पान की खेती करते हैं, और चामापाड़ा, जिसके निवासी भी कृपक हैं। अतएव पुराने गाँव का स्वरूप इस प्रकार के समुदाय का था, जो विशेष प्रकार की खेती पर निर्भर करता था। इस पर औद्योगिक स्वरूप थोपा गया। रिसड़ा १८६५ में सेरामपुर नगरपालिका का हिस्सा था। सन् १९०० में रेलवे स्टेशन की स्थापना होने पर ही इसका मुख्य रूप से विकास हुआ। इस सम्बन्ध में कारखानों के विकास का विश्लेषण (विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ १२९ पर दी हुई तालिका देखें) करना रूचिकर होगा।

औद्योगिक विकास जूट मिलों की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ और बहुत अधिक तादाद में श्रम-स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी था। पहले से ही औद्योगिक परम्परा स्थापित ही जाने पर अन्य प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना अपेक्षाकृत आसान बन गया। विशेष विकास आजादी हासिल करने के बाद हुआ और ऐसा प्रतीत होता है कि हलके धातुकार्मिक सामान के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की मुख्य बात यह है कि बादवाले उद्योग रेलवे लाइन के दोनों ओर स्थापित हैं, जबकि नदी के किनारे स्थापित जूट मिलें

यातायाव के साधन के रूप में हुगली नदी का महत्व अधिकार अब औद्योगिक उपयोग में आती है। श्रमिक प्रकट करती है। ग्राण्ट ट्रक रोड पर अवस्थित प्रेसीडेन्सी जूट मिल बाद में स्थापित हुई, किन्तु कच्चा माल बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से आती है। सामान्यतः इस आबादी में अनेक जातियाँ हैं। श्रमिक भर्ती करने का तरीका इस प्रकार है मिल जाँबर के जरिये सम्पर्क साधती है, हो सकता है कि वह

औद्योगिक इकाई	स्थापना वर्ष	कर्मचारी
वेलिंग्टन जूट मिल	१८५५	३,८६१
हैस्टिंग्स जूट मिल	१८७६	४,५००
प्रेसीडेन्सी जूट मिल	—	—
ए सी सी आय (आय सी आय)	१९३१	१,४००
जयश्री टेक्सटाइल्स	१९४४	३,०००
श्री राम सिल्क मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	१९४८	३००
यनाइटेड वेजीटेबल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी	१९४८	—
कलकत्ता फॉसफेट कम्पनी लिमिटेड	१९४८	—
लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	१९५२	१,०००
जे के स्टील	१९५२	—
बगाल वायर नेटिंग फैक्ट्री	१९५२	—
श्री इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स	१९६०	३००
गोविन्द स्टील कम्पनी लिमिटेड	१९६२	३००
श्री दयाल पोर्सेलैन वर्क्स	१९६२	—

है। इनमें से कुछ के मालिक अग्रेज थे, किन्तु बाद में वे कारखाने भारतीय व्यापारियों को हस्तांतरित कर दिये गये।

श्रमिकों की भर्ती

भौतिक दृष्टि से इस औद्योगिक संगठन या व्यवस्था का परिणाम निकला है आबादी का पृथक्करण अथवा विसंयोजन। जहाँ जमीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों से रिक्त है—वार्ड एक ओर दो—वहाँ श्रमिक वस्तियाँ हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में भी अविकारियों, श्रमिक चालो और कारखानों के लिए मकान हैं। पान के बागीचों के अन्तर्गत भूमि बहुत कम हो गयी है। उसमें से

उस मिल का कर्मचारी ही हो। गाँवों से नये श्रमिक भर्ती करने के लिए वह जिम्मेदार होता है। स्वाभाविक रूप से ही वह अपने गाँवों की ओर से श्रमिक लाता है, जो प्रायः पारिवारिक तौर पर उसके सम्बन्धी होते हैं। इसके लिए वह जो सेवा प्रदान करता है, उसके बदले में प्रति श्रमिक कुछ शुल्क लेता है। इस प्रकार लाये गये व्यक्ति अकुशल होते हैं। उन्हें शिशिक्षु प्रशिक्षण दिया जाता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस प्रकार के अनेक जाँबर हैं। किन्तु जहाँ तक बड़े प्रतिष्ठानों का सवाल है, जहाँ कि कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की

भर्ती एक श्रमिक भर्ती अधिकारी के जर्जिये की जाती है। वह प्रतिष्ठान का वेतन भोगी कर्मचारी होता है।

प्रथम तरीके से भर्ती किये गये श्रमिकों में सामुदायिक गठन और ठोस ग्रामीण सम्बन्ध होते हैं। प्रायः किसी विशिष्ट कुशल समुदाय की तकनीक ज्ञान के सम्बन्ध में परम्परागत पृष्ठभूमि होती है, जैसे वस्त्र मिलों में बुनकर, जोकि प्रायः सभी उत्तर प्रदेश के मुसलमान कारीगर हैं। श्रमिक आबादी के स्थानांतरण के सम्बन्ध में जो भी पृष्ठभूमि हो, उसमें समूह के लिए विशिष्ट तरजीह पायी जाती है। उन्हें जबर मिल की तरफ से मकानात नहीं मिलते तो वे अपने प्रदेशवालों—जैसे छपरा, बलिया, पटना, गोरखपुर, प्रतापगढ़ अथवा अन्य ऐसे ही स्थानों में आये हुए व्यक्ति जोकि किन्हीं काम मुहल्लों में रहते हैं—के मोहल्लों की ओर जाना पसन्द करते हैं। सकटकाल अथवा होली या मुहर्रम जैसे त्यौहारों पर जो पारम्परिक मदद ली-दी जाती है, उस वक़्त ये विशिष्टताएँ अधिक स्पष्ट रूपेण दृष्टिगोचर होती हैं, तथापि मालिक और मजदूरों के मध्य खड़े होनेवाले श्रमिक विवादों या झगड़ों के दौरान मजदूर सब इन विभागों को पार कर जाते हैं तथा तरोताजा निष्ठा निर्मित करते हैं।

सामाजिक पृथक्करण

प्रारम्भिक बोरी, ढेकी और चासा आबादी में मात्र २० परिवार ही खेती करते हैं। शेष कारखानों में काम करते हैं। बगाली व्यक्ति कारखानों के दफ्तरो में काम करते हैं। उन्हें स्थानीय रूप से अथवा सेरामपुर, कोन्नागार और चन्द्रनगर में भर्ती किया जाता है। आर्थिक स्तर का विन्यास इस प्रकार है श्रमिक—गैर बगाली, कार्यालय कर्मचारी—बगाली, और कार्यपालक—गैर बगाली।

श्रमिक दलों की भांति सामाजिक पृथक्करण उच्च स्तरों पर भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, रिसडा महिला मण्डल नामक एक महिला सघ आस-पास के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करनेवाले कार्यपालका की श्रीमतियों का सगठन है। इसकी कुल सदस्य-संख्या ३६ है। इनमें केवल तीन ही बगाली हैं। अन्यक्ष तथा मंत्री गैर बगाली हैं। एक अन्य सगठन रोटेरी क्लब है। इसके अन्तर्गत वाली में वैद्यावती तक का क्षेत्र आता है। इसके सदस्य जूट मिलों से लेकर मोटर आदि का उत्पादन करनेवाले कारखानों तक के कार्यपालक हैं। कुल सदस्य २१ हैं, जिनमें चार बगाली हैं और अन्यक्ष गैर बगाली हैं।

नव आर्थिक स्तर विन्यास

परिवर्तनशील आर्थिक पद्धति में शहरी सगठन के स्थान-विषयक वितरण में एक नयी पेशेवर सघटना का विकास हुआ है। आबादी-स्वरूप में भी एक परिपूर्ण परिवर्तन आ गया है। नवीन आर्थिक स्तर विन्यास में, उत्पादन क्षेत्र में मजदूरों की नयी संस्था का जन्म हुआ है और सामुदायिक हितों के अनेक रूप हैं। इनमें में कुछ अभी शहरीकरण द्वारा मुक्त नहीं हुए हैं। उदाहरणार्थ, रिसडा में जो श्रमिक हैं उनमें अब भी अपने जिले की भावना पायी जाती है। इस प्रकार शहरीकरण के नये स्वरूप और काम-धंधों ने मानवीय सम्बन्धों के स्वरूप में भी एक नयी परिवर्तन प्रक्रिया प्रारम्भ की है, जिसमें जानि, गाँव अथवा जिले सम्बन्धी पहलू के सम्बन्ध धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं।

मितव्ययी तिलहन एकत्रण की ओर

पु. वि. श्रीकण्ठ राव

तिलहन एकत्रण कार्य का संगठन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एकत्रकर्ता की उचित आय सुनिश्चित हो और औद्योगिक तथा अन्य कार्यों के लिए तिलहन का उपयोग करनेवाले का उत्पादन सस्ता हो।

लगभग गत पाँच वर्षों में देश में अखाद्य तिलहन सम्पत्ति के संरक्षण की आवश्यकता अधिक महसूस की जाने लगी है, यद्यपि भूतपूर्व अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल द्वारा अखाद्य तेल और साबुन उद्योग के विकास का कार्यक्रम १० वर्ष पहले आरम्भ किया गया था। यद्यपि इन तिलहनो के उपयुक्त एकत्रण, भाण्डारीकरण तथा प्रशोधन के लिए अनेक कदम उठाये गये और अनुप्रेरणाएँ दी गयी, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था में 'स्तरीय एकत्रण' की अनुक्रिया बड़ी मन्द रही। 'स्तरीय एकत्रण' का लक्ष्य बनाते समय दो परस्पर विरोधी तत्वों पर उचित ध्यान देना चाहिए—पहला यह कि तिलहन एकत्र करनेवालों की उचित आय सुनिश्चित होनी चाहिए और दूसरा यह कि तिलहन का प्रशोधन खर्च ऐसा होना चाहिए जोकि उसका औद्योगिक अथवा अन्य कार्यों में उपयोग करनेवालों को स्वीकार्य हो। इन दोनों को संतुलित करना सरल काम नहीं है। इस समस्या का एक निदान है हमारी कार्य-पद्धति के अनुरूप बनाने के लिए तकनालाजी को सरल बनाना। प्रक्रिया को अधिक तेज करने के लिए जहाँ कहीं भी सम्भव हो, किसी भी आवश्यक हद तक शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी क्रियाओं में समय का बड़ा महत्व है।

आज अधिकांश तिलहन एकत्रकर्ता की मौजूदगी मौसम के साथ-साथ बदलती रहती है। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि तिलहन एकत्रकर्ता और तिलहन प्रशोधन में लगे लोग साल दर साल यही कार्य करें। चन्द्र क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में तिलहन एकत्र होता है

या बड़ी मक्या में लोग इस काम में लगते हैं और अल्प काल में ही (लगभग एक महीने में) अच्छी रकम मजदूरी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि यह अल्प आयवाले परिवारों को अतिरिक्त आय कराने की दृष्टि से एक सफलता है, तथापि यह अकेले ही ऐसी मजबूत नींव नहीं डाल सकती, जोकि किसी भी औद्योगिक क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिलहन एकत्रण की अवधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि मौसम में एक व्यक्ति कितनी आय कर लेता है। समस्या है यह देखना कि इस आय में पर्याप्त वृद्धि की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक स्वरूप को तदनु रूप व्यवस्थित करना ही पड़ेगा।

भाण्डारित तिलहन

प्रथम एवम् प्रमुख बात है यह समझना कि हम कहते हैं 'तिलहन एकत्रण' यद्यपि वह फल ही है जोकि पक जाने पर एकत्र किया जाता है। तिलहन शब्द का प्रयोग इस माने में महत्वपूर्ण है कि वह तिलहन ही है जो लम्बे काल के लिए भाण्डारित किया जा सकता है। इसीलिए फल को तिलहन में बदलने की आवश्यकता है। यदि कुछ हालात में तिलहन अर्थात् बीज भाण्डारित नहीं हो सकता हो तो व्यावहारिक रूप में गिरी या गूदा ही बीज का काम करेगी, किन्तु किसी भी हालत में फल बीज नहीं हो सकता है।

जब लक्ष्य तिलहन का 'स्तरीय एकत्रण' है तब एकत्रण खर्च उचित रूप में कम होना चाहिए। उचित रूप में कम का तात्पर्य है कि अन्तिम उत्पादन को ध्यान में

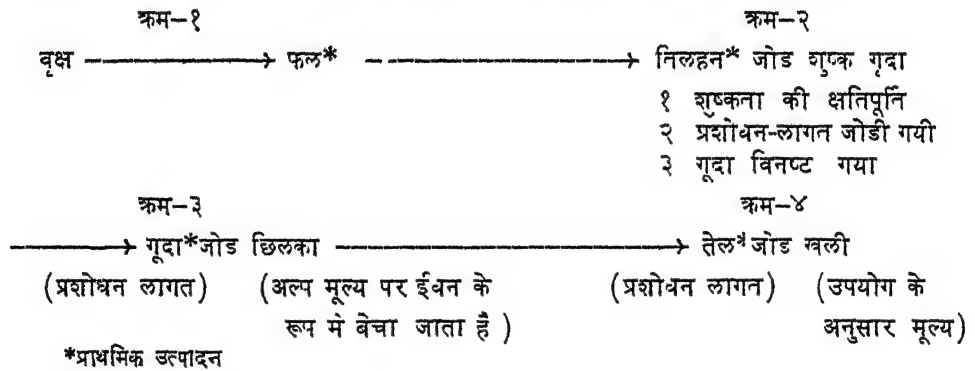
रख कर विभिन्न जाति के तिलहनो और क्षेत्रो के लिए लागत का विम्नृत स्वरूप तैयार किया जाना चाहिए। यह तभी संभव है, जबकि अन्तिम उत्पादन की लागत प्रसिद्ध तिलहनो तथा तेल के मूल्यों के परिवर्तनों के प्रभाववश नहीं हो। यह सवाल दूसरा है कि लागत के सामान्य स्तर और श्रम तथा समय-स्रोतों के रूप में निवेशों को ध्यान में रख कर देखा जाय कि क्या किसानों को उनके तिलहनो के लिए मिलनेवाला मूल्य उचित है।

तिलहन एकत्रण में सफलता को इसमें आँकन होगा कि किस हद तक कार्य-पद्धति ताजे फल एकत्रण को 'भाण्डाग्नि तिलहन' के रूप में परिवर्तित करने में सफल रही है। 'भाण्डाग्नि तिलहन' एक महत्वपूर्ण

वाक्यांश है जोकि सिर्फ बड़ी मात्रा में तिलहन एकत्रण की ओर ही सकेत न करके ऐसे तिलहन की ओर भी सकेत करता है जो लम्बे समय तक अच्छी हालत में सुरक्षित रखा जा सकता हो। इसका महत्व इस अर्थ में है कि भाण्डाग्नि तिलहन अच्छा तेल प्रदान करने में क्षम्य हो जिसका मतलब यह है कि उनका तेल-तत्व अनुकूलतम होना चाहिए और आर्द्रता तथा मुक्त स्नेहाम्ल का क्रांतिक अनुपात रासायनिक तौर पर स्वीकृत मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

खाव-सूचिका : वृक्ष से तेल तक

निम्न खाव-सूचिका प्रत्येक क्रम पर प्राथमिक उत्पादन और अन्तिम उत्पादन प्रदर्शित करती है



वृक्ष फल देनेवाले प्राथमिक स्रोत है। फल गुच्छों में रहते हैं और शाखाओं के अन्त में मिलते हैं। पकने पर वे पेड़ से गिर जाते हैं और कभी-कभी तेज हवा या आँधी के कारण वे अध पकी अथवा कच्ची स्थिति में ही गुच्छे से अलग हो कर गिर पड़ते हैं। फलों के पकने तथा जमीन पर गिरने में तीन से चार सप्ताह और कभी-कभी उससे भी अधिक समय लगता है। सीधे-सीधे वृक्षों से ही फलों को प्राप्त करना आदर्शपूर्ण है। किन्तु चूँकि कभी-कभी पेड़ लम्बे होते हैं और फलों के गुच्छे फुल-गिये पर होते हैं, ऐसी स्थिति में पेड़ों पर चढ़ कर उनको तोड़ना संभव नहीं, क्योंकि पेड़ की वे शाखाएँ आदमी का भार वहन नहीं कर सकती। मध्यम श्रेणी के वृक्षों के लिए हँसिया लगे हुए बासों का प्रयोग किया जा

सकता है। किन्तु इसमें पेड़ों को क्षति पहुँच सकती है। इसलिए फलों को पेड़ों से स्वाभाविक तौर पर गिरने पर ही एकत्र करना पड़ता है। पेड़ के नीचे की भूमि की सफाई और फलों को हाथ से तोड़ने से वाह्य अशुद्धियों को खत्म किया जा सकता है, जोकि जमीन से बटोर कर एकत्र करने से नहीं हो सकता है।

फलों को हाथ से तोड़ने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वह आदर्शपूर्ण तरीका है जबकि बटोरने की पद्धति से एकत्रण में बाहरी चीजों का आना अवश्यम्भावी है। ये बाहरी चीजें-पत्थर, टहनियाँ, फूल-लागत तो बढ़ाती ही हैं और यदि उन्हें उम्मी हालत में कुछ समय तक छोड़ दिया जाय तो फल पर बुरे प्रभाव भी डालती हैं। कच्चे फल हवा की वजह से या फल के गुच्छे के

अग के पेड से अलग हो जाने के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं। पके फल का रंग (पीला) कच्चे फल के रंग—जोकि कुछ हरापन लिए हुए होता है—से भिन्न होता है। विभिन्न किस्मों के फलों का निरीक्षण करके कोई भी सूक्ष्म दृष्टि इस भिन्नता को सहज ही पहचान सकती है। व्यापारिक एकत्रण में उनको अलग-अलग करना कठिन होगा, वह अधिक समय लगानेवाली प्रक्रिया है।

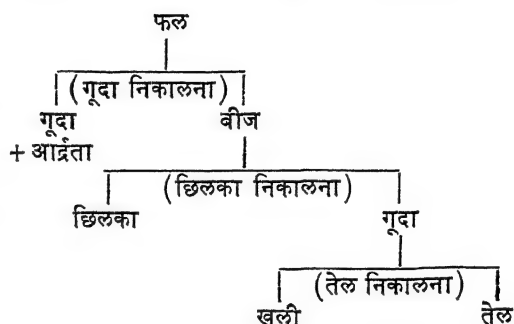
उन फलों के तिलहनो में जिनके छिलके टूटे-फूटे हैं, हवा तथा आर्द्रता प्रवेश कर जाती है और गूदे को प्रभावित करती है। गूदा जारित होकर दुर्गन्धित हो जाता है। इसलिए यह सावधानी बरतनी चाहिए कि छिलका टूटे-फूटे नहीं।

धल से भरे फलों से मालूम होता है कि गूदे में मिट्टी लगी है और अन्दर का छिलका टूट-फूट सकता है। जब आधी-पानी आता है, तब जमीन पर गिरे हुए फल मिट्टी से भर जाते हैं। उनको पानी से साफ करके शीघ्र सुखाना चाहिए। किन्तु सबसे अच्छा तरीका है उनका गूदा शीघ्र निकालना। पानी में फल को भिगोने से ऐसे वाह्य तत्व निकल जाते हैं जोकि पानी से अधिक वजनदार हैं, जबकि अन्य तत्व फल के साथ पानी में तैरते रहते हैं। इनको दूर करने के लिए चलनी का उपयोग किया जा सकता है।

अतः इस दिशा में एकत्रण के समय ही कदम उठाये जाने चाहिए, जिससे स्तरीय एकत्रण सुनिश्चित हो सके। इसके लिए एक विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है, जोकि धैर्यपूर्ण तथा प्रवीण मार्गदर्शन में संचालित किया जाना चाहिए। यह क्षेत्र के लोगों से सीधे-सीधे सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए पर्याप्त सम्भावना प्रदान करता है। यदि कम से कम इतना प्राप्त हो जाय तो अच्छे श्रेणी के फल का एकत्रण बहुत-कुछ सुनिश्चित हो जाय।

गूदा निकालने, सुखाने, छिलका निकालने, ओसाने और तेल निकालने की प्रक्रियाएँ तकनालाजी, कार्य पद्धति, तकनीक, उपकरण, औजार और सबधित लोगों की तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती हैं।

प्रशोधन के दौरान प्राप्त विभिन्न उप-उत्पादनों, जैसे एकत्रित फलों के विभिन्न भागों के उपयोग की सम्भावनाओं की खोज करने की भी काफी गुंजाइश है। उदाहरणार्थ, निम्बौरी के बारे में निम्न स्नाव सूचिका कार्य की विभिन्न स्थितियों में उत्पत्ति व प्रक्रियाएँ प्रदर्शित करती हैं



प्रथम स्थिति में फल से गूदा निकाला जाता है और सुखाया जाता है। यदि फलों से प्राप्त गूदे का कुछ उपयोग हो सके तो फल से गूदा निकालने की लागत पूरी की जा सकती है। जिस हद तक यह किया जा सकता है उस हद तक तिलहन एकत्रण लागत को कम किया जा सकता है। उसी तरह जिस हद तक छिलके, खली और बाद में उपोत्पादन से आर्थिक अर्ध्र्य प्राप्त किये जा सकते हैं उस हद तक तेल—जोकि अन्तिम उत्पादन है—का मूल्य नियंत्रित किया जा सकता है।

हर क्रम—गूदा निकालने, छीलने तथा तेल निकालने—में प्रशोधन लागत कम करनी चाहिए। इस के लिए यंत्र तथा उपकरण योग्य होने चाहिए, ताकि कम से कम समय में अनुकूलतम उत्पादन सुनिश्चित हो सके।

उपकरणों तथा औजारों की सविरचना के साथ-साथ, प्रशोधन के हर क्रम में अनुकूलतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह उनके इस्तेमाल की योग्यता को सुनिश्चित करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। उन्नत उपकरणों, तकनीकों तथा कार्य पद्धति शुरू करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम लागू करना चाहिए, जिससे कि उनका उपयोग

करनेवाले लोग नवीन प्रवृत्तियों को आत्मसात कर सकें। इस प्रसंग में प्रचलित कार्य-पद्धति के अध्ययन और नयी कार्य पद्धति न अपना कर उसमें ही सुधार करने की सम्भावनाओं की खोज के लिए उठाये गये कदम सही प्रयास होंगे। इस प्रकार कुछ समय बाद उन्नत तथा नवीनतम उपकरणों व तकनीकों को लागू करना सहज होगा। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अखाद्य तेल और साबुन उद्योग निर्देशालय द्वारा गठित तिलहन प्रशोधन पर्यवेक्षण इकाइयाँ इस दिशा में सही कदम हैं। ये इकाइयाँ प्रचलित पद्धतियों के बारे में आधारभूत आकड़े प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई हैं।

सावधानी बरतने के बावजूद हर क्रम में उत्पादन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाने की सम्भावनाएँ हैं। आदर्श फल या बीज अथवा गूदा की परिभाषा क्षम्य अशुद्धियों के अनुपात के साथ करनी चाहिए। यह इकट्ठे फलों और तिलहनो के ढेर के निर्धारण को सरल बनायेगा। फलों या तिलहनो के स्तर के अनुकूल मूल्य दिये जाने चाहिए। सम्पत्ति, सारे देश के लिए समान मान नहीं है। यह हर क्षेत्र में भिन्न है, परन्तु एक सामान्य मान निश्चित करना है। तिलहन प्रशोधन पर्यवेक्षण इकाइयों द्वारा एकत्रित आकड़े इस दिशा में उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं।

समाजशास्त्रीय पहलू

मित्तव्ययी तिलहन एकत्रण की समस्या के अन्य पहलू भी हैं। अनुकूलतम स्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए किये गये समस्त प्रयासों—गुणात्मक, परिमाणात्मक तथा तकनालाजीकल—के बाद भी यह निश्चित नहीं माना जा सकता कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। जब कार्य पद्धति को कार्यरत किया जाता है, तो उसमें सर्वदा पीछे रह जाने का तत्व रहता है, क्योंकि समस्त अनुवर्ती क्रिया अन्ततोगत्वा स्थानीय लोगों पर निर्भर करेगी। एकत्रण एवम् प्रशोधन कार्य में सर्वदा व्यक्तिगत तत्व होता है, जोकि स्थानीय लोगों द्वारा मानक तकनीकों की ग्रहण-शीलता तथा प्रयुक्तता पर निर्भर करता है। साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि तिलहन एकत्रण प्राकृतिक स्थिति व प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भर

है, जिन पर सामान्य स्थिति में नियंत्रण रखना कठिन है।

कृषि प्रक्रियाओं के विपरीत, जहाँ किसान अपने को कुछ ज्ञान तत्वों—जैसे उपलब्ध भूमि का विस्तार और उसकी किस्म, जमीन जोतने, बोनो और कटाई के समय तक फसल की देखभाल करने की उसकी क्षमता तथा उत्पत्ति का ज्ञान—का भान रहता है। ये अखाद्य तिलहन वृक्ष सर्वत्र बिखरे हैं और समस्त स्रोतों का एकत्रीकरण तथा उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्थान-स्थान तथा पेड़-पेड़ तक जाना पड़ता है।

कृषि में सहायक

अखाद्य तिलहनो की समस्त अनुमानित सम्पत्ति में नीम का हिस्सा आधा है। इसे ५ लाख टन ताजे फल मानने में मूल्य करीब तीन करोड़ रुपये होता है। समस्त अखाद्य तिलहनो में २८ करोड़ रुपये की कीमत के दो लाख टन अखाद्य तेल प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही कृषि के लिए खाद के रूप में उपयोग करने लायक ४ लाख टन खली भी मिल सकती है। एक एकड़ भूगफली की फसल में अन्दाजन २०० पौंड तेल मिलता है। दो लाख टन अखाद्य तेल २२ लाख ४० हजार एकड़ भूगफली क्षेत्र के बराबर होगा। चार लाख टन खली धान और गन्ने की चार लाख एकड़ फसल में खाद का काम दे सकती है।

अतः अभी आवश्यकता यह है कि अखाद्य तिलहनो के इस स्रोत का पूर्ण उपयोग किया जाय। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी असफलता के कारणों का पूर्ण विश्लेषण होना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय या तकनीकी हो सकते हैं, जैसे असाक्षरता कार्यक्रम के प्रति उदासीनता, पर्याप्त आर्थिक आकर्षण का अभाव, वित्तीय कमी और आर्थिक नेतृत्व। इनको युद्ध-तत्परता के स्तर पर चलाना पड़ेगा। हमारे संगठन की शक्ति हमारी इस तत्परता में निहित है कि हमारे कार्य में छोटे से छोटे दोष को अच्छी तरह ठीक किया जाय और हमारी सफलता इस बात पर निर्भर रहेगी कि किस हद तक कार्यक्रम व्याप्त हो गया है।

बम्बई २७ अगस्त १९६३

समृद्धि की दुविधा *

सुभाष चन्द्र सरकार

हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन से ही उसका जीवन बड़ा परिश्रमी रहा है, जिसमें उसे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए निरन्तर सघर्ष और कठोर श्रम करना पड़ा है। अधिकांश मानविक शक्ति जीवन की अत्यावश्यकताएँ पूरी करने में लगती थी। बहुतों को कष्टमय जीवन बिताने के लिए मजबूर किये बिना कोई आराम में नहीं रह सकता था, क्योंकि उपलब्ध रसद सीमित थी और उसे बढ़ाया नहीं जा सका। जहाँ कुछ लोग धनी थे, वहाँ बहुतों को गरीब होना ही पड़ता था। कुछ दिनों पूर्व तक सब जगह के लोगो के लिए यह सत्य था। औद्योगिक क्रान्ति ने प्रथम बार उन सम्भाव्यताओं का मार्ग प्रशस्त किया, जिनके जरिये राष्ट्र न सिर्फ अपनी आवश्यकता भर, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उत्पादन कर सके। प्राविधिक विकासो ने गरीबी और असमानता को अनावश्यक बना दिया है। अनेक देशों में यह सिद्ध किया जा चुका है कि आधुनिक तकनालाजी का उपयोग कर काफी हद तक गरीबी दूर की जा सकती है। इसी प्रकार असमानता भी दूर की जा सकती है, क्योंकि अब हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन करना सम्भव है।

गरीब-अमीर का अन्तर जारी

दुर्भाग्यवश ये सम्भावनाएँ विश्वव्यापी रूप से कार्य रूप में परिणत नहीं की गयी हैं। अभी भी बहुत बड़ी आबादी घोर गरीबी में रहती है और मसार के सर्वाधिक

समृद्ध देश से भी असमानता समाप्त नहीं हुई है। सर्वाधिक समृद्ध देशों में गरीबी का भौगोलिक वितरण तथा असमानता का रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व की करीब आधी आबादी विश्व की कुल आय का १६ प्रतिशत ही प्राप्त करती है, दूसरी ओर सिर्फ १५२ प्रतिशत लोग ही विश्व की कुल आय का ४५ प्रतिशत प्राप्त करते हैं (सिर्फ ७७ प्रतिशत आबादी कुल आय का २८ प्रतिशत प्राप्त कर लेती है)। जैसे कि यह अवस्था अधिक खराब नहीं है, गरीब देशों में धनी देशों की अपेक्षा धीमी गति से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, जिससे गरीब और धनी देशों का अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अनेक देशों में राष्ट्रीय रूप से भी विभिन्न आय वर्गों के बीच के बड़े अन्तर की यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति धीरे-धीरे स्पष्ट हो गयी है। इसलिए, प्राविधिक सम्भाव्यताओं के बावजूद राष्ट्रीय दायरे में भी समृद्धि उतनी ही अपवाद स्वरूप रह गयी है, जितनी कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में।

यह एक असाधारण स्थिति है, और मानव के सुखी भविष्य के लिए इसमें शीघ्र सुधार करना ही चाहिए। इस समस्या के दो पहलू हैं—राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय। प्रत्येक राष्ट्र में सर्व साधारण जनता का जीवन-स्तर उन्नत करने और असमानता कम करने का हर प्रयास किया जाना चाहिए। विश्व की वर्तमान स्थिति में, जबकि देशों को विश्वव्यापी प्रतियोगिता करनी पड़ती है, यह उद्देश्य प्राप्त करना बहरहाल किसी भी तरह सहज नहीं है। कई राष्ट्र आधुनिक तकनालाजी को जन-सेवा में प्रयुक्त करना बहुत ही मुश्किल पाते हैं। प्रथम, इसलिए कि उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं है और न वे साधन हैं जिनसे कि यह ज्ञान खरीद सके, जोकि अधिक मांग होने के कारण

* अमेरिका एण्ड दि वर्ल्ड रिवोल्यूशन, लेखक आर्नाल्ड टायनबी, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंडन, १९६२, पृष्ठ १७, मूल्य १९ शिल्लिंग ६ पेंस।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जितने में बिकना चाहिए था, उसमें कहीं अधिक महंगा है, और द्वितीय, न सिर्फ विकसित और अल्प विकसित देशों के बीच, बल्कि अल्प विकसित देशों के बीच आपस में भी, दिन प्रति दिन प्रतियोगिता कड़ी होती जा रही है, जिसका अल्प विकसित देशों की विकास क्षमता पर असर पड़ रहा है। दूसरी बात को और स्पष्ट करने के लिए भारत-चीन के संघर्ष का उदाहरण लीजिए, जिसमें निश्चय ही भारत के विकास की गति पर असर डाला है और उसी तरह चीन-रूस संघर्ष ने चीन की प्रगति पर। इससे समस्या के दूसरे पहलू की ओर ध्यान जाता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहकार की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। अधिक समृद्ध राष्ट्र कई तरह से लाभदायक योगदान दे सकते हैं। आधुनिक विश्व में दो बड़े राष्ट्र हैं—अमेरिका और रूस। केवल पश्चिमी शक्तियों और रूस द्वारा ही निःशस्त्रीकरण से विश्व कल्याण के लिए बृहत राशि और ऊर्जा प्रसारित हो सकती है, यह “धनी राष्ट्रों को उनके वर्तमान भय और गरीब राष्ट्रों को उनकी वर्तमान कमियां में छुटकारा दिलायेगा।” (पृष्ठ ७१)

प्रचुरता के जरिये पृथक्त्व

सन् १९६१ के बसंत में पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय में दिये गये अपने तीन सार्वजनिक-व्याख्यानो में डा आर्नोल्ड टायनबी (Arnold Toynbee) ने, जोकि उक्त पुस्तक में प्रकाशित किये गये हैं, अमेरिका के कर्तव्य पर प्रकाश डाला है, जिसके पास इस आधुनिक विश्व में बहुत बड़ी उत्पादक शक्ति है। अमेरिका ने समकालीन विश्व में अपनी जिम्मेदारियों को कहाँ तक आका है और कहाँ तक पूरा किया है? डा टायनबी कहते हैं कि अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभायी हैं। यद्यपि अमेरिका के स्वातंत्र्य युद्ध ने विश्व भर में दिलचस्पी जगायी थी, अब वह जबकि धनी हो गया है इस क्रान्ति युग में ससार भर से मिले प्रत्युत्तर के प्रति उत्साही नहीं है, जिसने कि सर्वत्र गरीब किसानों के दिल में हलचल मचा

दी थी। डा टायनबी के शब्दों में अमेरिका “अल्प-संख्यकों में शामिल हो गया है” और “अब बढ़ती हुई क्रांतिकारी शक्तियों, जिनका उसने खुद ही निर्माण किया था, के विरुद्ध उसने जो धन संचय किया है उसकी रक्षा के लिए वह अपने को बाध्य पाता है।” (पृष्ठ १८)

मांग सीमित करना आवश्यक

यह पृथक्त्व धन के कारण हुआ है। (यह जानिवाद के कारण भी हो सकता है। डाक्टर टायनबी ने बताया है कि एक भारतीय हिन्दू ब्राह्मण प्राध्यापक उनके साथ भोजन करने में बचता था, क्योंकि वे ईसाई थे।) मन् १९२८ तक अमेरिका ने देशान्तरवास कानून बना कर, जिसने कि यूरोपवासियों के (एशियावासियों को अमेरिका में बसने की इजाजत तो कभी थी ही नहीं) देशान्तरवास पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। “यह स्वयं पृथक्करण, इस बात का भान होने का कि ‘वह धनी हो गया है तथा फिर अपने इस नये कल्याण की रक्षा करने के लिए कदम उठा रहा है’ का अनिवार्य दंड है।” (पृष्ठ २६-२५) फिर भी, इस समृद्धि का रूस क्या है? आज अमेरिका में जितनी खपत होती है वह लोगों की सही व्यक्तिगत आवश्यकता से कहीं ज्यादा है। (“हमारी मांगें अब भी हमारी जरूरतों में बहुत अधिक हैं, जबकि वे विज्ञापन माध्यमों के कृत्रिम प्रोत्साहन से प्रभावित नहीं हैं।” (पृष्ठ ६९) और, बृहत उत्पादन शक्तियों को बनाये रखने के लिए, जोकि सामान्य कल्याण के लिए आवश्यकताओं का उत्पादन करने के लिए स्वाभाविक मार्ग नहीं खोज सकी तथा जोकि कम आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन में लग गयी है, मांगों को विज्ञापन उद्योग के जरिये कई गुना अधिक बढ़ा-चढ़ा दिया गया है। डा टायनबी लिखते हैं, “अमेरिका में सही मांग और वास्तविक खपत के बीच कितना अन्तर है, उसकी प्राप्ति मांग निर्माण उद्योग के पैमाने से होती है, जोकि मैडिसन एवेन्यू में (जहाँ प्रमुख विज्ञापन कार्यालय स्थित हैं) चलता है।” (पृष्ठ ५६) इसका परिणाम सुखद नहीं हुआ है।

निरन्तर बढ़ती मांग को कुछ सीमित करना आवश्यक

हो गया है। डा टायनबी चेतावनी देते हैं, “अमेरिकी जीवन मार्ग ‘जॉच’ करने की अवस्था पर आ पहुँचा है” (पृष्ठ ६७), क्योंकि वह मनुष्य के सही लक्ष्य, जोकि आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति है, की प्राप्ति में मदद नहीं देता। जबकि मनुष्य का अस्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है, उन मांगों की पूर्ति की कोशिश करना—जोकि प्राथमिक आवश्यकताएँ नहीं हैं—जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। आध्यात्मवाद ही मनुष्य को मानवीय बनाता है। ससार से गरीबी दूर करने की सम्भावनाओं ने इन आध्यात्मिक क्षमताओं को—मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पहले से बहुत ही सहज बना कर—प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। भूखे मर रहे लोगों को जब अन्न दिया जाता है, तो वे अत्याहारी हो सकते हैं, परन्तु अत्याहारी होना स्वास्थ्यकर नहीं है।

प्रचुरता प्राप्त करने में सर्वप्रथम, अमेरिकी यदि पहली पीढ़ी में अपने को उपभोक्ता सामग्रियों में ही बाहुल्यता की ओर प्रवृत्त करते तो यह समझना कठिन नहीं है। परन्तु अत्याहारी होने की तरह यह लिप्सा भी स्वास्थ्यकर नहीं है और इसलिए वाछनीय भी नहीं है, आगे चल कर इससे विवेकशीलता आने ही वाली है। डा टायनबी कहते हैं, “पश्चिमी देशों की भावी पीढ़ियाँ पश्चिमी इतिहास के इस अंश पर आश्चर्य और अरुचि से गौर करेगी।” (पृष्ठ ७६)

ससार के सबसे बड़े जीवित इतिहासकार के विश्लेषण पर पूर्ण गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। डा टायनबी अमेरिकी श्रोताओं के बीच भाषण कर रहे थे,

इसलिए उन्होंने अमेरिका के ही उदाहरण दिये। लेकिन हर राष्ट्र को यह विश्लेषण अपने क्षेत्र में प्रयुक्त करना ही चाहिए, ताकि वह अपनी गलतियाँ सुधार सके। अत्याहारी होने से, भले ही अमेरिकी हो अथवा भारतीय, सभी जगह एक समान बुरे परिणाम निकलनेवाले हैं। यह समझना सबसे बड़ी गलती होगी कि कम उन्नत राष्ट्रों को प्रमुख खपत के विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम भारतवासी यह जानते हैं कि घोर गरीबी होने के बावजूद दिखावटी खर्च एक दुर्गुण बन चुका है। अमेरिकी सिर्फ अपने ही प्रयासों से अत्याहार और असमानता को दूर नहीं कर सकते, उन्हें अन्य राष्ट्रों की मदद भी लेनी ही होगी। इस सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम समृद्ध राष्ट्रों पर है। एक प्रकार से अमेरिकी जीवन (जिसे डा टायनबी विलासी जीवन कहते हैं) की विलासिता से बहुत दूर रहने के कारण अल्प विकसित राष्ट्रों के लोग अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि वे उस अनुभव से सीख सकते हैं और विज्ञापन के जरिये निर्मित कृत्रिम मागवाले समाज के दोषों से बच सकते हैं। सतुष्टि का दर्शन हम भारतीयों के लिए—जिन्हें शताब्दियों से ऋषि-मुनियों और दार्शनिकों के ज्ञान-संदेश प्राप्त है—एक लम्बे अरसे से जीवन-मार्ग का एक अंग बना हुआ है। हाँ, व्यवहार में कुछ समय से इस पोषित आचरण के प्रति कुछ विमुखता दिखायी पड़ रही है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे परिपूर्ण रूप से व्यवहार में लाना सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाये जाय।

बम्बई २ सितम्बर १९६२

हम अपने पाठकों और लेखकों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने खादी ग्रामोद्योग के प्रस्तुत वार्षिकांक के लिए हमारे आग्रह का आदर कर लेख भेजने की कृपा की। खेद है कि स्थानाभाव के कारण हम सभी लेख इस वार्षिकांक में प्रकाशित करने में असमर्थ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि खादी ग्रामोद्योग के आगामी अंक में हम उन्हें प्रकाशित कर सकेंगे।

—सम्पादक

पुस्तक समीक्षा

एस्पेक्ट्स ऑफ इकनॉमिक चेंज एण्ड
पॉलिसी इन इण्डिया • १८००-१९६०,
लेखक वी वी भट्ट, एलाइड पब्लिशर्स प्रायवेट
लिमिटेड, बम्बई, १९६३, पृष्ठ १२+१६०,
मूल्य १०.५० रुपये।

इस वर्ष के प्रारम्भ में डा भट्ट द्वारा बडौदा के
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में दिये गये
तीन व्याख्यान, जोकि इस पुस्तक का सार हैं—विशेष कर
ऐतिहासिक अंग का—काफी रुचिकर पाठ है। यद्यपि
वे किसी प्रकार का आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन नहीं
करते, तथापि गत १५० वर्षों में देश में आर्थिक
नीति एवम् विकास के ऐतिहासिक अनुभव का अकाट्य
सारांश अवश्य पेश करते हैं। और, यह ज्ञान केवल
शास्त्रीय रुचि का ही विषय नहीं है। विकास की प्रक्रिया
को उपयुक्त दृष्टिकोण से देखने तथा वर्तमान नीतियों
एवम् प्रवृत्तियों का बुद्धिमत्तापूर्ण मूल्यांकन करने की
अभिलाषा रखनेवाले व्यक्ति के लिए इतिहास का
ज्ञान जहाँ तक उसके द्वारा विकास की गति को निय-
त्रित करनेवाली दीर्घ कालीन अनिवार्यताओं व परि-
सीमाओं का उद्घाटन होता है वहाँ तक आवश्यक है।
डा भट्ट ने यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त तथ्य एकत्र
किये हैं कि “स्वतंत्रता-पूर्व के गत १५० वर्षों में प्रति
व्यक्ति आय में होनेवाले परिवर्तनों के अनेक लक्षणों
एवम् अनुमानों के मापन से जाहिर होता है कि भारतीय
अर्थ-व्यवस्था आर्थिक गतिहीनता अथवा हो सकता है
आर्थिक अवनति के दौर में गुजर रही थी।” (पृष्ठ २८)
लेखक द्वारा पुस्तक में उल्लिखित राष्ट्र-स्रोतों में

ज्ञान होता है कि साम्राज्य के दिनों में अधिक
विचारवान अंग्रेजों में से भी कई अवनति की इस प्रक्रिया
में भिन्न थे। विलियम विल्सन हण्टर ने १८८० में
कहा था, “हस्त लिखित दस्तावेजों में प्राप्त तथ्यों से वर्त-
मान ग्रामीण भाग की तुलना करने पर मैं इस नतीजे
पर पहुँचने के लिए बाध्य हो गया हूँ कि भारत में आज
जीवन उस समय की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से हो गया है,
जब यह देश हमारे हाथ में आया था। सन् १९५१ के
पूर्व की लगभग एक शताब्दी में भारतीयों के परम्परागत
पेशे की अपरिवर्तनीयता में गतिहीनता की झलक मिलती है।

लेखक ने भारतीयों तथा अंग्रेजों के अकाट्य प्रमाणों के
आधार पर भारत में ब्रिटिश नीति पर गंभीर आरोप
लगाया है। ऐसा अनुमान है कि १७५७ से १९३९ तक
के काल में भारत की राष्ट्रीय आय का २ से ३ प्रति
शत भाग अनेक प्रकार के भुगतानों के रूप में इंग्लैंड
जाता था और उसके बदले भारत को कुछ भी नहीं
मिलता था। सामान्य अपवादों को छोड़ कर उस वक्त
की सरकार की नीति भारतीय उद्योगों के विकास में
यदि पूर्णतः विरोधी नहीं, तो अवरोधक अवश्य रही है।
विदेशी पूँजी देश के अर्थतंत्र के विकास में सहायक होने
के बजाय बाधक ही रही है। लेखक महोदय ठीक ही इस
परिणाम पर पहुँचे हैं कि “भारत में आर्थिक गतिहीनता
की व्यापक व्याख्या यह हो सकती है कि राज्य अपनी
उचित भूमिका निभाने में असफल रहा।” (पृष्ठ ५८)

योजनाबद्ध विकास के दशक पर लिखते हुए डा भट्ट
ठीक ही कहते हैं कि “आर्थिक विकास एवम् सामाजिक-
राजनीतिक स्थायित्व के लिए, प्राण्य अतिरिक्त जन-शक्ति
का पूर्ण उपयोग अवश्य होना चाहिए।” (पृष्ठ १०१)

जन-शक्ति के प्रभावशाली उपयोग के बारे में डा भट्ट कहते हैं कि इसके लिए “किसी तरह के प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होगी” (पृष्ठ १०३), जिसे अति-रिक्त जन-शक्ति को उत्पादक कामों के निमित्त संगठित करने का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। उनका विश्वास है कि पंचायत राज संस्थाएँ सतोषजनक रूप से ऐसा कर सकती हैं।

—सुभाष चन्द्र सरकार

* * *

एक्शन रिसर्च एण्ड इट्स इम्पॉर्टेन्स इन एन अण्डर-डेवलप्ड इकनॉमी. प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इन्स्टीट्यूट, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, १९६३, पृष्ठ ७४, मूल्य का उल्लेख नहीं।

‘कृति-शोध’ (एक्शन रिसर्च) का तात्पर्य है मौलिक तथा प्रयुक्त शोध के परिणामों को बुद्धिमत्तापूर्वक आर्थिक तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में विस्तृत करना। यह वैज्ञानिक ज्ञान का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के साथ समन्वय करना है यानी उक्त ज्ञान को प्रस्तुत परिस्थितियों के अनुरूप बनाना तथा उसमें संशोधन करना। इस अर्थ में उक्त ‘कृति शोध’ पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, जोकि लोगों द्वारा शोध परिणामों के अपनाने अथवा अस्वीकार करने की अभिप्रेरणा तथा आचरण में बहुत बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकती है। तथापि, भारत की संस्कृति, जलवायु तथा अर्थ-व्यवस्था की विभिन्नता की स्थिति ही ‘कृति शोध’ की (जो विविष्ट परिस्थितियों का हल प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है) उपयोगिता अति वाछनीय होते हुए भी भारत जैसे देश के लिए न्यून कर देती है, क्योंकि जो हल एक प्रकार की परिस्थितियों में उपयोगी है, शायद वह भिन्न परिस्थितियों में सतोषजनक परिणाम न दे। ‘कृति शोध’ को उपयोगी क्रियाशीलता की मान्यता देने के पूर्व यह निश्चय करना आवश्यक है कि उसके परिणामों को बिना अनावश्यक लागत के व्यवहार में लाया जा सके। यह स्पष्ट है कि इस तरह का आश्वासन मंगलतापूर्वक नहीं दिया जा सकता और इससे देश

में इस प्रकार की शोध का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। यह उद्देश्य सुनिश्चित करने का एक उपाय यह है कि यथा संभव विस्तृत क्षेत्रों में ‘कृति शोध’ केन्द्र कायम किये जायें। उत्तर प्रदेश की जन सहयोग मूल्यांकन समिति ने भी यह माना है, पर अन्ततोगत्वा वही साधन-स्रोतों की उपलब्धि का प्रश्न आ खड़ा होता है।

सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश सरकार के योजना विभाग के अन्तर्गत लखनऊ में ‘दि प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इन्स्टीट्यूट’ का प्रारम्भ निम्न लिखित समस्याओं पर शोध करने के लिए हुआ (१) जन-दृष्टिकोण, (२) पंचायत, सहकारी समिति तथा विद्यालयों जैसी ग्राम्य संस्थाएँ, (३) कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योग, (४) सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई, (५) भू-रक्षण तथा भू-उपादेयकरण सहित कृषि, (६) पशुपालन, (७) लघु सिंचाई, (८) ग्रामीण आवास, (९) युवक, महिला तथा शिशु-कल्याण, और (१०) परिवार नियोजन। भारत में इस प्रकार का यह प्रथम संस्थान है।

लखनऊ स्थित ‘प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इन्स्टीट्यूट’ के निर्देशक डा राम दास ने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने इस रचना में ‘कृति शोध’ के सिद्धांत व व्यवहार की व्याख्या की है तथा गत वर्षों में संस्था द्वारा किये गये कार्य का संक्षेप में वर्णन किया भी है।

—सु च स

* * *

इकनॉमिक अफेयर्स (एक अर्थशास्त्र विषयक मासिक), योजना अक, वर्ष ८, अंक ७ और ८ (जुलाई-अगस्त १९६३), सम्पादक हिमामर राय, ५११डी, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-६, पृष्ठ ८२, मूल्य १ ५० रुपये। (वार्षिक शुल्क १० रुपये)।

विशुद्ध अर्थशास्त्र से सम्बन्धित मासिक पत्रिकाओं में ‘दि इकनॉमिक अफेयर्स’ विशेष उल्लेखनीय है। इसकी उपयोगिता तथा मूल्य तो इसी तथ्य से सिद्ध होता है कि अब इसका आठवाँ वर्ष चल रहा है। विशुद्ध अर्थशास्त्रीय पत्रिका प्रकाशित करने

मे आनेवाली कूठिनाइयों पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है और सम्पादक महोदय— जिन्होंने इन वर्षों में गत्रिका चलायी है—प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसी पत्रिकाओं के सम्पादकों के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई होती है, उक्त विषय पर प्रकाशित करने योग्य लेखों का अभाव। श्री राय ने अपने अथक प्रयास से देश भर के ऐसे लेखकों की रचनाएँ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, जो इस विषय में सैद्धान्तिक सूचि-ज्ञान और समझ बढ़ाने के लिए—रखते हैं।

प्रस्तुत योजना अरु में उदीयमान अर्थशास्त्रियों की रचनाएँ संगृहीत हैं।

—सु च स

*

+

*

कोऑपरेटिव पालिस्की एण्ड प्रोप्रेटर्स :

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया, नयी दिल्ली, १९६३, पृष्ठ १८९, मूल्य का उल्लेख नहीं।

यह केन्द्रीय सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय के सहकारी विभाग द्वारा राज्य सरकारों के सहकारिता विभागों के सचिवों को प्रेषित सहकारी नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण पत्रों का संग्रह है। पत्र कई परिच्छेदों में सकलित कर प्रत्येक परिच्छेद में कालक्रम से समाविष्ट किये गये हैं।

ग्रामीण समितियों के गठन के पीछे कल्पना यह थी कि वे मुख्यतः अल्प कालिक तथा मध्य कालिक ऋण, कृषि विषयक तथा अन्य प्रकार की उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति और कृषि उत्पादनों की बिक्री की व्यवस्था करेगी। ऐसे सगठन के लिए अनुपयुक्त छोटे गाँवों को छोड़ कर समस्त गाँवों में सहकारी समितियाँ बनाने की योजना थी। सहकारी समितियाँ आवश्यक रूप से

ही व्यापारिक सगठन होने के कारण उन्हें ग्राम पंचायतों, जोकि लगान के स्रोत में युक्त तथा कर लगाने की शक्ति से सम्पन्न प्रशासनात्मक सगठन हैं, से अलग रखा जाना था। सहकारिता की स्वयम् प्रकृति, उसमें अधिक में अधिक गैर सरकारी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने तथा सहकारी विधि एवम् कार्य पद्धति में सरलता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा कि श्री ब्रह्म प्रकाश ने पुस्तक की भूमिका में उल्लेख किया है कि सहकारिता प्रसार में अनेक कार्यकर्त्ताओं—जिन पर कार्यक्रम को लागू करने का बड़ा उत्तरदायित्व है—को भाग्य सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी विकास कार्यक्रमों व नीति-विषयक निर्णयों की विस्तृत जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में उक्त पुस्तक बहुत सहायक सिद्ध होगी।

—सुभाष चन्द्र सरकार

+

*

*

कोऑपरेशन अँज ए रेमेडी फॉर करल

पावर्टी : एम नुरुल हक, ईस्ट पाकिस्तान कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, ढाका-२, १९६३, पृष्ठ ३९, मूल्य १२५ रुपये।

यह रिविशा-चालको की एक सहकारी समिति (दि काशीनाथपुर बलरामपुर दीदर श्रमिक समवाय समिति लि) का यथा तथ्य अध्ययन है, जो १९६० के प्रारम्भिक काल में कोमिला स्थित ग्रामीण विकास के लिए पाकिस्तान अकादमी के तत्वावधान में सगठित की गयी थी। लेखक के अनुसार सहकारी समिति बहुत सफल रही। किन्तु अप्रभावकारी लेखनी से पाठकों के समक्ष उसका पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं होता है।

—सु च स

सम्पादक - सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय,' इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५९ से प्रकाशित तथा मुद्रित। मुद्रण-स्थल एसेसिएटेड एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टर्स, ५०५, तारदेव, आर्थर रोड, बम्बई-३४। वार्षिक शुल्क २५० रुपये, एक प्रति २५ नये पैसे। इस अंक के दो रुपये।



	Page
THE TENTH YEAR	1
SPECIAL FEATURES OF SOCIAL AND ECONOMIC DISPARITIES IN INDIA	—U N Dhebar 5
PLANNING—GANDHIAN APPROACH	—Vaikunth L Mehta 11
THE STATE OF RURAL ECONOMY	—Morarji Desai 16
EDUCATIONAL PROGRESS AND INDUSTRIALIZATION	—K Arunachalam 20
PROGRAMME FOR INDUSTRIES IN RURAL AREAS	—T N Singh 27
PROBLEMS OF RURAL CREDIT	—B Mukerji 30
IMPACT OF KHADI ON OUR ECONOMY AND SOCIAL ORDER	—Arun Chandra Guha 37
WHITHER KHADI?	—Dhwaja Prasad Sahu 42
FUTURE OF KHADI	—R K Patil 45
MISSION OF KHADI	—Jhaverbhai Patel 49
POTENTIALITIES OF AMBAR CHARKHA	—Shankarlal Banker 57
A PLEA FOR REALISM	—J D Sundram 62

(Continued on next page)

Editor S C Sarker Published and printed by him from Gramodaya, Irla, Bombay-56 Brought out by the Khadi and Village Industries Commission, *KhadiGramodyog* is a non-profit-making journal devoted to discussion on rural economics, sociology and development The editor would be glad to consider articles on these and allied topics, written from an objective angle Accepted contributions will be paid for Manuscripts of articles, books for reviews, etc, should be addressed to the editor, *KhadiGramodyog*, Gramodaya, Irla, Vile Parle (West), Bombay-56 Telephone No 86773

Opinions expressed in articles published in this journal do not, unless specifically indicated, necessarily represent the views of the Khadi and Village Industries Commission or of the editor

Annual subscription Rs 2 50 Single Copy Re 0 25 This issue Rs 2 Remittance of subscription should be sent to the Asstt Accounts Officer (Cash), Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, Irla Road, Vile Parle (West), Bombay-56

CONTENTS (*Continued*)

	Page
EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT DURING LAST FIFTEEN YEARS	— <i>B N Datar</i> 70
INVESTMENT AND CAPITAL ACCUMULATION IN INDIA	— <i>Amrita Datta</i> 76
VILLAGE INDUSTRIES IN TRIBAL AREAS	— <i>B H Mehta</i> 92
AGRICULTURAL RESEARCH AND RURAL ECONOMY	— <i>A R Khan</i> 97
OUR BONE RESOURCES	— <i>S K Barat</i> 100
RURAL EMPLOYMENT AND THE PLAN	— <i>Chittapriya Mukherjee</i> 104
ROLE OF SCIENTISTS AND ENGINEERS IN RURAL INDUSTRIALIZATION	— <i>M Sadashiva Rao</i> 114
A NEW LOOK AT INDIA	<i>G S Raychaudhuri</i> 120
PROBLEMS OF WOMEN'S EDUCATION	— <i>S Shrivdevi</i> 123
SOME ASPECTS OF URBANIZATION IN BENGAL	— <i>Meera Guha</i> 128
TOWARDS ECONOMIC SEED COLLECTION	— <i>P V Shrikanta Rao</i> 134
DILEMMA OF PROSPERITY	— <i>Suhhash Chandra Sarker</i> 139
BOOK REVIEWS	142

Aspects of Economic Change and Policy in India 1800-1960—V V Bhatt

Action Research and its Importance in an Underdeveloped Economy—Planning Research and Action Institute, Planning Department, Government of Uttar Pradesh

Economic Affairs (A monthly Journal of Economics) Plan Number—Himanser Roy, Calcutta

Cooperative Policy and Programmes—National Cooperative Union of India, New Delhi

Cooperation as a Remedy for Rural Poverty—M Nurul Huq, East Pakistan Cooperative Union Ltd, Dacca

Our Contributors:

UCHHRANGRAI NAVALSHANKER DHEBAR	—	<i>Chairman, Khadi and Village Industries Commission</i>
VAIKUNTH LALLUBHAI MEHTA	—	<i>Member, Khadi and Village Industries Board</i>
MORARJI RANCHHODJI DESAI	—	<i>former Finance Minister, Government of India, Member of Parliament</i>
KANDASWAMY ARUNACHALAM	—	<i>Vice-Chairman, Khadi and Village Industries Commission</i>
TRIBHUVAN NARAYAN SINGH	—	<i>Member, Planning Commission</i>
BRAHMADEV MUKERJI	—	<i>Managing Director, State Bank of India, Bombay</i>
ARUN CHANDRA GUHA	—	<i>Member of Parliament, Chairman of Estimates Committee of Lok Sabha</i>
DHWAJA PRASAD SAHU	—	<i>Member, Khadi and Village Industries Commission</i>
RAMKRISHNARAO KRISHNARAO PATIL	—	<i>Member, Khadi and Village Industries Board</i>
JHAVERBHAI PURUSHOTTAM- BHAI PATEL	—	<i>Member, Khadi and Village Industries Board</i>
SHANKARLAL GHELABHAI BANKER	—	<i>veteran constructive worker</i>
JOSEPH DURAI SUNDRAM	—	<i>former Director of Economic Research, Khadi and Village Industries Commission, at present Secretary, Indian Institute of Bankers, Bombay</i>

(Continued on next page)

OUR CONTRIBUTORS—(Continued)

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| BHAGWANT NAGESH DATAR | — | <i>Chief (Labour and Employment), Planning Commission, Government of India, New Delhi</i> |
| AMRITALAL DATTA | — | <i>Assistant Director (Research), Tariff Commission, Bombay</i> |
| BEHRAM HORMASJI MEHTA | — | <i>Professor of Research, Tata Institute of Social Sciences, Director, Gondwana Centre, Integrated Programmes of Social Services and Education for Tribal Welfare</i> |
| ABDUR RAHIM KHAN | — | <i>Head of Division of Agricultural Extension, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi</i> |
| SISIR KUMAR BARAT | — | <i>Assistant Director, Central Leather Research Institute, Madras, Member, Leather Advisory Committee of Khadi and Village Industries Commission</i> |
| CHITTAPRIYA MUKHERJEE | — | <i>Lecturer in Cooperation, Rural Higher Institute, Sriniketan</i> |
| MANJESHWAR SADASHIVA RAO | — | <i>Director, Rural Engineering Branch, Khadi and Village Industries Commission</i> |
| GAURI SHANKAR RAYCHAUDHURI | — | <i>Lecturer in Economics, University of Delhi</i> |
| SRIPATI SHRIDEVI | — | <i>Principal, University College for Women, Hyderabad</i> |
| MEERA GUHA | — | <i>Lecturer in Geography, Calcutta University, Calcutta</i> |
| PULLE VISHWANATHA SHRI-KANTA RAO | — | <i>Director, Non-Edible Oils and Soap Industry, Khadi and Village Industries Commission</i> |
| SUBHASH CHANDRA SARKER | — | <i>Editor of "Khadi Gramodyog" and "Jagriti" published by Khadi and Village Industries Commission</i> |

THE TENTH YEAR

Khadigramodyog enters the tenth year of its march with this issue. The journal was started a little over a year and a half after the All India Khadi and Village Industries Board had been set up by the Government of India with a view to organizing the scattered artisans engaged in the traditional industries in the villages and helping them to improve their lot through technical training and financial and other types of assistance. Invariably it takes some time for a new body to set up its organisation, especially so when the organisation has an all-India interest. In a sense, therefore, the tenth anniversary of the journal can be considered to be the tenth anniversary of systematic efforts to promote khadi and village industries.

The past decade has been momentous for the nation's development. It has been marked by political and economic consolidation and integration and planned measures for the economic and social well-being of the population. This was also the period when deliberate steps were taken to associate rural population with the processes of decision-making through the introduction of the panchayat raj. The dominating trend of the decade was the emphasis on planning.

The assessment of the achievements in the field of khadi and village industries has to be made in the context of the general progress of the economy. Despite the efforts made the general picture has been one of relatively slow pace of change and development in the rural sector of the economy. Agriculture has not yielded any marked response to efforts to raise productivity and produc-

tion. Since the bulk of the rural population, as is true of the population in general, is dependent on agriculture, the slack growth of agriculture is bound to find reflection in other fields of village enterprise.

The failure of agriculture to catch up with the process of development generally reflects the difficulties with which the decentralized sector of the economy has to contend. The programme of khadi and village industries has been spread over a lakh of villages. Ten years ago only about ten thousand villages had been covered. The production of khadi (including silk, woollen and ambar) rose from 115.63 lakh square yards in 1953-54 to 762.02 lakh square yards in 1961-62, registering a rise of more than 559 per cent. Employment in khadi went up from 3.79 lakh persons in 1953-54 to 17.46 lakh persons in 1961-62—a rise of more than 360 per cent. The progress in the field of other village industries has also been remarkable. In 1961-62 khadi and other village industries provided employment to 23.6 lakh persons of whom 74 per cent were employed in the khadi sector. Likewise, sales of khadi registered a fourteen-fold rise during the nine year period. Assistance was provided for the training of over half a million persons.

There is no doubt that the wages that a person can earn on khadi and the traditional village industries are very low and compare unfavourably with those in many other sectors of employment. But the important point to note is that there is no obligation on the part of anybody who can find better employment to take to these industries. Gandhiji

had categorically stated, "Handspinning does not, it is not intended that it should, compete with, in order to displace, any existing type of industry, it does not aim at withdrawing a single able-bodied person, who can otherwise find a remunerative occupation from his work" There has been no departure from this Gandhian stand The economic reality found eloquent reflection in the statement made by the Union Minister for Planning on 26 August, 1963 wherein it was disclosed that the poorest ten per cent of the population had a monthly per capita expenditure of eight rupees in the rural areas and ten rupees in the urban areas, that is, a daily per capita expenditure of 4 3 annas (a little over 27 naye paise) in the rural areas and thirty-three naye paise in the urban areas According to that statement in the rural areas seventy per cent of the population could spend only less than fifty naye paise per day And more than eighty per cent of the population live in villages In other words, 25 19 crores of people do not have as much as even fifty naye paise per day per head to spend According to the eleventh round of the National Sample Survey the per capita monthly expenditure of the rural population was Rs 16 97—or just a little over 56 naye paise per day There was however considerable regional variation from Rs 14 91 in Central India to Rs 21 75 in Northwest India Similar variation was observable in the case of urban incomes as well

The statistics quoted by the Union Minister for Planning related to the period from September 1961 to July 1962, when the seventeenth round of the National Sample Survey was conducted It may be recalled that the data on per capita incomes obtained during the ninth round of the Survey conducted in 1955 had indicated that 20 crores of people in the rural areas had a per capita

income of Rs 175 per year, that is less than fifty naye paise per day The number of people in this low income group has thus risen by over five crores between 1955 and 1962 This cannot be considered to be a sign of economic progress In other words, if employment opportunities can be created which would enable people to earn more than eight annas per day per head, the effort would be quite worthwhile Judged in this manner the relevance of khadi and village industries will be properly realized The Khadi and Village Industries Commission is not, contrary to the impression given by the critics, unmindful of the need to help raise the income of spinners who are among the lowest income group The Commission has taken a decision to introduce a model of charkha which would yield a daily per capita income of one rupee The model will be introduced as soon as it is perfected

Questions are often raised about the impact of the programme on the national economy The allocation for khadi and village industries during the first plan period amounted to Rs 14 82 crores which worked out at 0 44 per cent of the total plan provision A sum of Rs 84 crores (1 24 per cent of the total plan allocation) was allotted for khadi and village industries in the Second Plan The allocation for khadi and village industries of Rs 92 4 crores during the Third Plan works out at 0 78 per cent of the total allocation In other words, out of a total allocation of Rs 21,910 crores, in the three plans, only Rs 191 22 crores or about 0 87 per cent was allotted for the development of khadi and village industries A programme with an outlay of less than one per cent of the total planned outlay can hardly be expected to make a mark nationally There are particular areas in the country where the impact of the pro-

gramme can be properly studied. Again the permanence of the beneficial impact of the programme is dependent on the formulation and implementation of broader national policies. Even areas where the programme has been satisfactorily implemented can be disrupted by the introduction of mechanized units or by a change in policy. The recent decision to divert sugarcane to the production of sugar threatens the producers of gur.

The very nature of the programme of khadi and village industries puts an obligation on the Khadi and Village Industries Commission to deal with the relatively backward section of the village community, the members of which are economically weaker too. The various problems involved in administering the programme—making finances available to the needy section without affecting the security of the money thus advanced, making proper equipment available, providing facilities for repairing of equipment, training village artisans, inducing them to use equipments with which they may not be familiar, supervising production, arranging for marketing of products which have to be collected from villages not always situated in contiguous areas, and so on—would, on contemplation, appear in their true dimension and complexity which were enough to baffle the best initiative and intentions. The problems do not admit of any easy solution and many other agencies, besides the Khadi and Village Industries Commission have been trying their hands at them with no more remarkable success. Moreover it is to be noted that largely the Commission does not itself implement the programme. The implementation is made by the State Khadi and Village Industries Boards, cooperative societies and organisations registered under the Societies Registration Act. The principal func-

tions of the Commission are to provide financial assistance, technical guidance, and facilities for training of workers of societies and artisans. The extent to which the societies will succeed in their working depends on a number of other factors such as entrepreneurial and managerial ability the organisations can command, the skill with which they can face the fluctuations of the market in procuring raw materials and selling their products.

As has already been noted the efforts made during the past decade have not been entirely barren of good results. But that certainly offers no ground for complacency. In the Commission there is a constant stress on more and better work to widen the scope of operation of the programme and to enhance its meaningfulness for the rural masses. The Commission has been trying to coordinate its activities with those of other agencies working in the rural areas so as to maximise the results obtainable from their efforts. The awareness of this need for coordination is the guiding spirit behind the naya morh programme. In grappling with the most difficult problems of rural regeneration the need for constant vigilance and self-criticism can hardly be exaggerated. While ill-informed criticism of khadi and village industries is to be correctly deprecated, it is improper to refuse to discuss the various alternative courses of action open for their promotion. It is only if the workers engaged in the promotion of khadi and village industries discuss the alternatives with an informed and unbiased mind, can mistakes be avoided and the correct path found. No effort has, therefore, been made to exclude any criticism of the programme and the Commission in this volume which is intended to provide a general review of the rural economy.

The objectives of the journal had been des-

cribed by Shri Vaikunth L. Mehta in the first issue in the following words "Essential, however, as are State sympathy and support, the reorganisation that the (All India Khadi and Village Industries) Board (which has since been succeeded by the Khadi and Village Industries Commission) seeks and the positive contribution towards provision of wider employment that it wishes to make, are possible only when the thinking sections of the community, who largely influence the course of public affairs, come to understand and appreciate the significance of khadi and other village industries in our economic life. Hence one of the foremost tasks of the Board is to place before this section of our public

the khadi and village industries movement in its proper perspective, and, having aroused their interest, to seek their active participation in the great endeavour. The invaluable lesson in the fundamentals of our Indian economics that Gandhiji taught us, we can afford to forget only at peril to our social structure." They still remain our motto.

Our labours will have been rewarded if this volume helps even in a small measure a better realization of the relevance of the rural industries to any genuine effort for the improvement of the conditions of living of the masses and of the problems that have to be contended with in achieving that goal.

To believe your own thought, to believe that what is true for you in your private heart is true for all men,—that is genius. Speak your latent conviction, and it shall be the universal sense, for the inmost in due time becomes the outmost, and our first thought is rendered back to us by the trumpets of the Last Judgment. Familiar as the voice of the mind is to each, the highest merit we ascribe to Moses, Plato and Milton is that they set at naught books and traditions, and spoke not what men, but what they thought. A man should learn to detect and watch that gleam of light which flashes across his mind from within, more than the lustre of the firmament of bards and sages.

Ralph Waldo Emerson

SPECIAL FEATURES OF SOCIAL AND ECONOMIC DISPARITIES IN INDIA

U N DHEBAR

At the root of many inequalities obtaining in India is the social system which has been nourishing privileges for ages. Despite the efforts during the last 15 years the conditions in the country today are far from encouraging in both the social and economic fields. Poverty still stalks the land in many regions. For 30 per cent of the population it is a question of survival. The struggle to eliminate disparities is a struggle for self-survival on the part of our teeming millions. Khadi, village industries and animal husbandry will help in toning down the imbalance in the economy.

MANY things are responsible for inequalities in income and wealth. There are some inequalities which are due to personal factors. Nature has not made us all alike. Intellectual capacities differ from individual to individual. There are other factors which relate to the qualities of head and heart. They also affect the standing in life of a person. The spirit of adventure also plays its own part. These qualities give to a person advantage over others and some inequalities do result from them. This however cannot be complained against.

But there are inequalities which are objectionable and have to be prevented or removed. Personal qualities have little to do with these inequalities. They arise due to factors for which an individual cannot take personal credit. They originate in birth, class, caste, religious status, hierarchy, profession and other extraneous factors. A dunce, born at a rich man's place, is rich because he is a rich man's son and not because he has some personal qualities which entitle him to the

riches that he possesses. The cadets in a feudal system automatically come into possession of land simply because they happen to be the sons of the landholder. A Harijan is always at a disadvantage because of caste considerations. In the age of priestly domination, religion played its own part. Some professions have a honoured place and yield fat incomes out of all proportion to the service they render to the society.

Inequitous Social System

In short, certain privileged positions—may be because of social, economic, political or hierarchical reasons—automatically give a certain advantage. This is because of the character of the social system. It upholds the right of persons possessing these privileges and bypasses the claims of others. At the root of many inequalities obtaining in India is the social system which has been nourishing privileges for ages which give advantage to certain persons or groups and deny opportunities to others. This has brought about dis-

parities in wealth and incomes in India to an extent we rarely find in any organised society of the world

II

Privileged Classes

The picture of India of 1963 was not the picture of our country in 1947. In 1947 we had social groups which were enjoying, under the protection of the then prevailing imperialist system, vast privileges which gave them a certain standing and status in life. This system simultaneously denied to vast masses of India opportunities which would enable them to develop. The imperialist system in its very nature, was an exploitative system and lived and flourished by monopolising opportunities of life in the hands of a few. Next to the imperialist group came the landed gentry. The princes of India for instance enjoyed a position of eminence in the political and economic field in nearly one-third of India which no one else did. The social system thus lent its unqualified support to the social order under which they predominated and in which hardly any opportunities were given to the bulk of the people in their principalities. The princes' younger brother in that social system was a zamindar. He also made for imbalance in the social structure by claiming a privileged position in the social structure and denying to his tenants any opportunity. The bulk of the peasantry in India which constituted nearly three-fourths of the country was then a victim of the social system.

The members of the scheduled castes constituted another group of persons disinherited in the name of religion. Scheduled tribes which were disinherited because of policy reasons—a policy enunciated by the

then imperialist Government of inflicting political segregation upon them—was another group. The labour was also at the mercy of the employment market. The endemic unemployment and underemployment left hardly any choice for it but to accept what wages were offered.

In between these two groups—groups of socially privileged persons and socially exploited persons were the middle classes. They were also living a life of great strain socially economically and politically.

Gandhiji's Leadership

This unnatural situation was not going to last long. Soon the masses began to show signs of frustration began to lose their initiative and appeared for a time completely demoralised. It was a magic of Gandhiji's leadership that he could in the midst of such demoralisation revive new hope and courage and succeed in mobilising them for the struggle of independence which was to end the hold of imperialist system upon this country and many others.

III

Changes for the Better

Fifteen years of rule by people's chosen representatives have changed the picture of India. The hold of imperialism has been completely eliminated and the Indian economy today is a free economy, politically speaking. The statesmanship of Sardar Vallabhbhai Patel has freed the country from the feudal hold also. Comparatively speaking, Indian farmer is a free individual in relation to his rights on land. The elimination of the imperialist feudal system had opened out opportunities of life to the vast numbers of people. Scheduled castes are

coming into their own. Segregation of the scheduled tribes is being eliminated. The factory labour is assured of its dues. There has been a rise in incomes both agricultural and industrial. There has been expansion of educational opportunities on a very substantial scale. Amenities are available to a wider circle of people than in the past. Sincere and earnest efforts are being made to fulfil the promise of democratic freedom to all the people of India through panchayati raj institutions and through cooperatives. There has been a growth of new consciousness among the people, generating new initiatives and opening new opportunities of life. Justice demands that due credit is given to those who have made all these possible.

IV

Shortfalls

There are shortfalls in some directions. They too are not universal. But there has been no doubt that the shortfalls exist. I do not think even those who are in charge of the destinies of the country deny their existence. I also do not think it will be proper or fair to hold them responsible unilaterally for these shortfalls. If anything, while their critics have nothing to their credit in the shape of constructive contribution, they have to their credit a decade and a half of service to the nation which has been responsible for the new opportunities of life which we enjoy today, apart from the vast obstacles which they have removed—obstacles which impeded the march of the nation towards progress till the other day.

If I am speaking about these shortfalls it is because these shortfalls have dangerous moral and social implications. The shortfalls can be traced in every direction of national life. It was our good fortune to

possess Gandhiji. He was an idealist, who combined in his personality a robust commonsense. By dint of hard work and personal sacrifice he generated an atmosphere in this country of service, without thought of self, to the down-trodden. He popularised spiritual incentives to take the place of monetary incentives. He generated a climate of simplicity. The greatest shortfall in the last 15 years of the country's life has been the shortfall at this level. Psychologically India of 1963 has little relation to the India of 1947 or of earlier years. The climate of sacrifice has given way to the climate of self-seeking. Values of service have been replaced by those of returns and rewards. The principle of cooperation is being replaced by the spirit of unhealthy rivalry. The objective frame of mind of individuals and groups has undergone a metamorphosis. The country lives in an atmosphere which is polluted by considerations of self, comfort, ease and arrogance. The whole picture is becoming more and more unseemly and unbecoming and therefore losing its grace and charm. It will be a mistake to suggest that this is confined to the political sphere. Nobody can point an accusing finger at another without someone else pointing the finger at him.

Whatever the sphere of our national life, by not adhering to Gandhiji's values of life and by trying to copy the standards of other countries, the nation has deprived itself of a greater potential factor which would have helped her immensely even on a mundane plane.

In Social Sphere

In the social sphere the conception of non-violence was acting as it were as a talisman for keeping the classes and the masses together, for keeping people belonging to different creeds and religions together, for drawing intelligent and illiterate masses towards

one another, for mixing rich with the humble and educated with the uneducated. We were beginning to feel that we constituted a society held together by new values of life—the values of cooperation, goodwill, sympathy, fellow feeling, bearing love towards one another and interested only in trying to improve the lot of the teeming millions of India's down-trodden. These values also gave us a few norms of discipline. It was a discipline of a new kind but it vested the nation with some kind of self-respect and dignity. The social recognition offered to those values and disciplines helped even common people to subscribe to those values and disciplines with ease. Those values have suffered not only at the psychological level but in the field of actuality also. The national life is once again at the mercy of those values which led it to its downfall.

At Economic Level

At the economic level also there have been shortfalls. India is losing two crores of man-days due to unemployment and under-employment and India will have to live with this picture of these losses for a long long time to come. Thirty per cent of our population in the lowest layer of society has to be satisfied with an income which cannot be considered to be sufficient for human existence and though this level is higher than what it was in 1947 and will go on progressively increasing, it will not be enough from the point of view of human existence for another quarter of a century or more. Large sections of middle classes are living a life of strain and will have to live under similar conditions for another 20 to 30 years. The question of disparities in incomes and

wealth requires to be considered in this context.

V

Tales of Poverty

What is the significance of these disparities? Some pictures arise before my mind. I was travelling with a beloved friend of mine, Shri Girdharlal Kotak, some five years back. It was lunch hour. We stopped our car on the way and entered a couple of huts. There were hardly any rations for the family in the first hut we entered and the mistress of the house in the second was surrounded by three or four children. She was waiting for the master to return before she could begin preparing the day's meal. Soft as he is Shri Kotak could not resist tears.

Another instance exactly parallel occurred in the month of July last. I was travelling in a car in the company of the chairman of a State Khadi and Village Industries Board. He was engaged in talking to me about the great change that had come over in the rural areas. To a certain extent this claim was justified. But I had a feeling that the chairman had not the whole picture before him. I, therefore, requested him to stop our car at the next village side. This was also lunch hour. In the first hut we entered the owner was a tenant cultivating four acres of land. There were six people in the family. They had had their midday meals and had preserved something for the evening one. On persistent inquiries by the chairman and after rummaging for about ten minutes he learnt that they had not even six seers of foodgrains in the house. We entered another house. The owner was again a tenant cultivating six acres of land. He told a similar tale. He had to borrow to sustain himself for three or four months in a year. The rate of interest

was 2½ per cent per month. We proceeded to the third house and heard similar stories. These are landless labourers of India constituting 17 per cent of our rural agricultural population and increasing with each decade as divisions take place in the families of our small landholders. Fiftyseven per cent of the agricultural holdings of India are below five acres each. With the passage of time they will also join the ranks of the landless labourers of India.

The scheduled castes can be divided into two groups. Those who do scavenging especially in the small towns are passing through a difficult period of existence. The remaining in the rural areas of India suffer the same fate as the landless labourers of India. The privations in which scheduled tribes live have been described in the Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission and I need not reiterate them here. The picture of squalor and filth in which the city slum-dwellers live is well-known. It is not easy to give a census of the footpath-dwellers in the big towns of India.

The disparities obtaining in a country have to be measured from the social and economic context of a nation's life. I have indulged in a long prologue about the social and economic conditions to convey the deep sense of urgency the situation demands. Disparities in our country cannot be explained away in mere economic terms. Have-nots of India are underfed and hungry. They constitute more than a third of India's population.

mic terms of a few morsels that a hungry man can get to satisfy his unsatisfied hunger. These morsels have a value of their own. They signify to the hungry the difference between a half belly and a full belly. To introduce considerations based on economic costs in that context is to play with the morsels of hungry man. No economic theory has so far been able to work out the cost of a bloody revolution to the famishing masses or the masses who live on the verge of sustenance. The reason is that the consideration of money has no relevance when it is a question of self-survival. For more than 30 per cent of the population in India it is a question of self-survival. A Government or an economist who argues on the basis of the principles of market economy only exposes his ignorance of the working of the law of human nature. These laws are different from the laws of economics.

The problem of helping the indigent masses of India is a problem both moral and political—moral in the sense of enabling a human being to stand on his own legs with his own efforts and a political problem of enabling our society to survive. The relevance of khadi and village industries has to be understood in relation to this moral and political crisis that obtains in India. Struggle to eliminate disparity in our own country is a struggle for self-survival on the part of our teeming millions. It is any time more acute than the struggle for toning down mere economic inequalities or avoiding merely concentration of wealth and power.

VI

Role of Village Industries

Struggle for Self-Survival

The role of side occupations in India has to be considered from that angle. No economist can describe the value in econo-

Village industries and animal husbandry are the two off-shoots of agricultural economy. They supplement the shortage of land. They tone down the imbalance in the rural

economy due to heavy pressure of population on land which is monthly and daily increasing. They make it possible for village people to exist, to survive. They also ensure occupations with the lowest possible capital investment. Side by side they provide opportunities for improving the technology and the tools and the methods used in their production. They help in steadily building up new initiatives and helping in promoting creativeness. They wear out feelings of dependence and frustration. In the process they are building up defences against possible eruption of violence which desperate condi-

tions can breed at any moment. No other national activity has been able to put the idle manhours of the vast masses to productive purposes as khadi and village industries have been able to do at the cost at which they have done. The Government that pays subsidy thus not only helps the individuals but also fulfils social purposes. The customer who pays a little higher price contributes not only towards sustenance of the individual family but also towards the survival of his country.

Bombay
11 September 1963

Economic equality is the master key to non-violent independence. Working for economic equality means abolishing the eternal conflict between capital and labour. It means the levelling down of the few rich in whose hands is concentrated the bulk of the nation's wealth on the one hand, and a levelling up of the semi-starved naked millions on the other. A non-violent system of government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists. The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor, labouring class cannot last one day in a free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land. A violent and bloody revolution is a certainty one day unless there is a voluntary abdication of riches and the power that riches give and sharing them for the common good. I adhere to my doctrine of trusteeship in spite of the ridicule that has been poured upon it. It is true that it is difficult to reach. So is non-violence difficult to attain. But we made up our minds in 1920 to negotiate that steep ascent.

Mahatma Gandhi

PLANNING—GANDHIAN APPROACH*

VAIKUNTH L MEHTA

The only criterion for judging the success of planning in our country, according to Gandhiji, is the extent to which our planning succeeds in securing for an increasing number of people the right to work and such basic necessities as food, decent clothing, pure drinking water, housing and educational facilities. This should also be the real test for evaluating the efficacy of the programmes for development.

IN this article it is not proposed to examine the concept of national planning, or the objectives and content of our five year plans as Gandhiji would have viewed them. Such an essay is fruitless, in any case it would be presumptuous for the present writer to attempt the task. But it would not be irrelevant to take note of the general approach of Gandhiji to social and economic planning. Leaving aside *Hind Swaraj* and Gandhiji's earlier writings, one may draw attention to his role at the historic session of the Indian National Congress held at Karachi in 1931. Being the first session to be held after the struggle for complete independence had been launched, our conception of the future pattern of society in India naturally engaged the attention of the nation's leaders, with Gandhiji at their head. Their views, which were not only endorsed but were expounded by Gandhiji, are set forth in the famous Karachi Congress Resolution on the National Programme. Gandhiji was thus not averse to formulating a plan of development for the country. The Karachi Resolution formed the basis of the national demand, when, with Gandhiji's approval, the Congress participated in elections under the Government of India Act of 1935

and its representatives assumed office in a majority of Indian Provinces in 1937.

Early Beginnings

Shortly after the assumption of office by Congress Ministries, the then President of the Congress, Netaji Subhas Chandra Bose constituted early in 1939 the National Planning Committee with Shri Jawaharlal Nehru as its chairman. Among the members of the Committee was Prof J C Kumarappa while the Committee on Cottage Industries had as its chairman Shri Satish Chandra Das Gupta—both of them close associates of Gandhiji. About the same time, there was published *Economic Planning for India* by Sri M Visvesvarayya. While applauding the earnestness and enthusiasm which the veteran engineer-statesman had brought to the production of this, the first study on the subject, Gandhiji expressed his dissent from the view that the core of economic planning was rapid intensified industrialization. Particularly did he object to the intensification of industrialisation of a type that prepared the ground for the manufacture of armaments.

It is significant that while the National Planning Committee was engaged in the drawing up of plans for the various facets

* Based on a talk at Maharashtra Gandhii Smarak Nidhi, Poona on 14 July, 1963.

of national development, Gandhiji placed before the country what he considered to be the essentials of his constructive programme based on the application of the twin concept of truth and non-violence. The social order, he sought to see established, was one founded on social justice. But the rule of economic equality was to be ushered in in a non-violent manner, for Gandhiji was convinced that any attempt to bring about a social revolution through violence would unchain forces that would endanger the social values of liberty and fraternity, which according to him, India ardently cherished. Pursuit of the constructive programme was the surest means of ensuring democracy at the grass-roots. Since the great majority of our people lived in villages it is their welfare, and the welfare of the lowest of the low, namely, Harijans that, he emphasised, should claim priority over other parts of the programme of social and economic development. Far-seeing, methodical and businesslike as he ever was, Gandhiji had always a plan for all he wanted to be done.

Objectives of Planning

The era of planning in our country may be said to have commenced with the inauguration of the republican Government of the country established under the Constitution of India. The Directives of State Policy enunciated in the Constitution in conformity with the Fundamental Rights enshrined therein made it incumbent on the Government of the country to plan for its social and economic development for implementing those Directives. For a country emerging from a colonial economy, with certain sections underdeveloped and the rural sector in conditions of stagnation, progress is well-nigh impossible, it was re-

cognized, in the absence of careful well-ordered planning. The National Planning Committee had defined the objectives—in terms which should have secured Gandhiji's endorsement—a decade before the Planning Commission was appointed. "The background or foundation of our Plan is the establishment of a full democratic state involving an equalitarian society in which equal opportunities are provided for every member for self-expression and self-fulfilment and an adequate minimum of a civilized standard of life is assured to each member so as to make the attainment of this equal opportunity a reality." In the reports on the Second and Third Plans the objectives have been elaborated and set forth in specific terms. Essentially, to quote the opening sentence in the Third Five Year Plan, "the basic objective of India's development must necessarily be to provide the masses of the Indian people the opportunity to lead a good life."

Means should not be confused with ends. The development of heavy industries, the production of steel, the expansion of oil resources, the generation of electricity are all instruments for securing the end. If life is to be made a fuller one for the millions, who despite 12 years of planning have barely enough for their sustenance, the indicators for measuring progress are different. Industrialization and power are all aids that are intended to secure the resources for making the life of the common man fuller. The highest priority, as was emphasised at a Seminar held at Poona in 1961 under the joint auspices of the Akhil Bharat Sarva Seva Sangh and the Gokhale Institute of Politics and Economics, should be accorded to the objective of providing work or employment for everybody willing to work, which would enable him to earn enough to

satisfy his minimum needs or to enable him to have a minimum of material well-being. That fits in with Gandhiji's conception of a *sarvodaya* order.

Problems of Agriculture

This postulates that the plan should be rural reorientated. In Gandhiji's Constructive Programme, the integrated development of the rural economy was the principal concern. It is true that Gandhiji had no specific programme for the reorganization of the agricultural industry. But in the Constructive Programme he laid stress on the need for adopting improvements in methods of agriculture for promoting which, individuals who could not, because of the size of their holdings, command the necessary resources, should be encouraged to resort to the co-operative form of organization. Cooperative farming, he advocated as a measure of economy called for under our present agrarian conditions. Cooperative organisation was also thought of by him for the maintenance of cows, for cow breeding and for increasing milk production. To the problem of land ownership, in the absence of a Government responsible to the people, he did not devote much thought. In the context of the changed conditions, Acharya Vinoba Bhave seeks to deal with the problem through a programme based on a change of heart, a maximum of voluntary effort and a minimum of State action.

In the objectives as defined in the Third Five Year Plan, though the need for the development of agriculture has been underlined, the emphasis laid on increasing production so as to provide raw materials for industries and to secure earnings from the export of agricultural commodities appears to be somewhat misplaced. We certainly want to get more out of the land to raise

the aggregate output from agriculture so that we may have self-sufficiency in the matter of foodgrains. Even more welcome, however, are the efforts to raise the level of production for the purpose of increasing the earnings from agriculture, and of reducing the gross disparities that prevail between the incomes from agriculture and those from urban industries, trade, commerce and from secondary or tertiary services.

Stress on Local Resources

Agricultural improvement does not consist in resort to mechanization for various agricultural operations or in the application of fertilizers to crops. Both may have their uses, but, as Gandhiji always used to insist, one must first ensure that all available local resources are fully utilized before resort is had to artificial aids. If human or bullock power is equal to carrying on certain operations it should not be replaced by mechanical aids. Similarly, the local manurial resources should be properly conserved and fully used before fertilizers which are scarce and costly are employed for raising levels of production. Conservation of manurial resources should be for the entire countryside an essential feature of all rural planning, just as soil conservation done with local labour and conservation of water resources through minor irrigation works should also be. The wealth from pursuit of animal husbandry can be augmented by the full exploitation of all the ingredients obtainable from the carcasses of fallen animals. A programme for carcass recovery will raise the social status and the level of incomes of those engaged in the disposal of dead animals, in flaying, in tanning and in other ancillary processes.

The main factor responsible for rural stagnation and the consequent deep-rooted

poverty of the country, Gandhiji held, was the decay of rural industries. Often he described the process as causing a double drain on the rural economy. The people in villages lost the income they derived from the pursuit of various supplementary occupations and subsidiary or principal industries producing goods which had a large demand both in villages and in towns. In order to meet their own consumption requirements they had to buy goods manufactured at home or abroad by parting with their hard-earned income when they could easily have produced the goods themselves and satisfied their own needs at much less cost. The revival of these occupations and industries was a major part of Gandhiji's constructive programme.

Hence, recognizing the role of cottage industries in our economy, provision was made for their development in the First Five Year Plan. In the Second Plan, the position was broadly accepted that an attempt should be made to ensure that as large a portion of the growing demand for consumers' goods entering into the daily life of the common man should be produced increasingly through rural and other cottage industries. The State, it was agreed, should adopt a policy of extending aid to these industries and affording to them protection against the products of organized large-scale industries. Although it cannot be claimed that a growing proportion of all varieties of consumers' goods in common demand is now supplied by rural and cottage industries, the last 12 years of planning have certainly witnessed a substantial rise in the employment provided through these industries.

The impact of this programme on the economy as a whole has admittedly not been

appreciable. After reviewing the progress achieved, Shri Jayaprakash Narayan urged at the Sarvodaya Sammelan of 1961 a more comprehensive approach to the problem of diversification of the rural economy, by taking in hand industries other than the traditional ones to produce the new types of consumers' and even producers' goods required not only in the countryside but in urban areas as well. To the extent possible these industries might depend on raw materials, agricultural and others, that were available locally. There should, however, be no restrictions placed on the use of raw materials obtained from outside the region of their location. The main purpose, of course, should be the provision of work of a suitable type for the surplus labour in villages so far as possible in the vicinity of their own habitats.

Rural Industrialization Commission

There should, moreover, be no bar to the application of improved techniques for the new or even for the traditional industries provided the introduction of these methods or appliances did not lead to the displacement of labour or provide scope for its exploitation. To put through such a comprehensive, dynamic programme Shri Jayaprakash Narayan urged the creation of a rural industrialization commission. By appointing a Rural Industries Planning Committee and approving of a phased programme for the intensified development of rural industries under a single agency responsible to the Planning Committee for execution of the approved plans, the Planning Commission has met the substance of the demand made.

This is a programme for decentralization of non-agricultural production with the

units of production dispersed and located in rural areas, owned and managed by the rural people themselves, through their co-operative organizations or panchayat agencies at various levels. But, as Gandhiji recognized, there are some forms of production that have to be conducted and controlled by a central authority in the interest of the national economy. Principally, these are what he described as key industries, what we now term as heavy industries. These are needed to give us the producers' goods and to generate the power which are essential for the strengthening and reinvigorating of our economy to meet the requirements of a modern society. Such industries, it was an article of faith with Gandhiji, should be nationalized, that is, they should be run under state ownership and control. In order that the centralization of authority should not lead to bureaucratization, and to the emergence of employer-employee relations, Gandhiji would have applied a remedy in the shape of the treatment of labour as a participant and a partner.

Trusteeship or State Action

Since 'sarvodaya' spelt the good of all, as distinct from the greatest good of the greatest number, Gandhiji did not visualize the complete extinction of business enterprises run by private individuals or their syndicates or corporations. But he called upon those in charge to look upon the workers as partners and as participants both in matters relating to conditions of work and in the division of the gains of the undertakings. While he valued the enterprise, acumen and ability of the businessmen in charge of undertakings, he adjured them to be trustees for the people. They should harness their skills to the concerns as public servants. This

postulates a change of heart on the part of those in charge of the undertakings in what is now known as the private sector. Failing the voluntary acceptance of the concept of trusteeship, there has to be regulatory action on the part of the community, to ensure that the objective is achieved.

Test of Progress

To the extent that planning subserves the ideals that Gandhiji upheld, and the social values that he cherished, one can claim that it proceeds in the direction in which Gandhiji desired India to move after the achievement of independence. But if we are carried away by the glamour of bigness, if we try to force the pace, if we seek to emulate the pattern of development in industrially advanced countries, if we allow unemployment and underemployment to stalk the land, and if we permit disparities in income and wealth to get widened, our planning may be said to have failed in its purpose, whatsoever the rate of growth of the gross national product and howsoever high the achievements recorded in the production of steel, the generation of electricity, the tapping of resources in oil, gas and coal or in the per capita absorption of consumers' goods such as radios and telephones. The sole test, not only according to Gandhiji but according to all who value progress in terms of the good life, is the extent to which planning succeeds in securing for growing numbers enough food, decent clothing, pure drinking water, a roof and four walls for shelter, a modicum of education, environments conducive to good health and, above all, the right to work for one's sustenance.

Poona
2 August 1963

THE STATE OF RURAL ECONOMY

MORARJI DESAI

There is no short or easy answer for conquest of poverty in our country. Agriculture which is the Heel of Achilles of development will have to be made productive and linked up with cottage, handicraft and other industries. Under democratic decentralization the masses will have to shoulder the responsibility of implementing the rural development programmes. The rural India of tomorrow should present a picture of economic prosperity and democratic participation.

IT is more than a decade since India launched on a course of planned economic and social development. We are now in the middle of the Third Five Year Plan. Behind all our plans lies a vision of the future, when India would be free from the curse of poverty and everybody in this country would be assured of opportunity to lead a good life. This is a vision which we have been carrying through since the long years of our national struggle for independence. Political freedom would mean little unless we also succeed in achieving freedom from want. It is in quest of this second freedom that the country has deliberately broken with past economic stagnation and has already taken the first steps along the long road to development.

Conquest of Poverty

To provide for a good life to more than 440 million people of India is no small undertaking. It is a colossal job and its achievement will take many more years. The conquest of poverty has no short or easy answer. It cannot come through one or two

quick and simple lines of action involving small numbers of people, however important they may be. Every part of the country's economy, its farms, its factories, its mines and forests must produce more. Its urban as well as rural sectors must change and develop.

Within the gigantic task of raising the living standards of India's masses, the problems of rural India are enormous by themselves. India is predominantly a rural nation and will remain so for many years. Nearly 80 per cent of India's population lives in villages. Without developing her rural sector, India's development will be incomplete and unreal. Indeed, the roots of India's poverty lie in its villages. To help India's rural people raise their living standards and build a better life is, therefore, an urgent social as well as economic goal. Rural prosperity is the bed-rock on which the nation's economic development must rest.

Measures for Improving Agriculture

Seven out of eight people in India's villages depend on farming as a way of life

and livelihood. Nearly half of India's national income derives from agriculture, as compared with nine per cent in the U S or 18 per cent in Japan. Modernisation and development of agriculture holds the key to rural prosperity and even the nation's development. In the Third Five Year Plan we have accorded top priority to agriculture. Indeed, over the next fifteen years or so agricultural development is bound to be given high priority. Since the commencement of planned economic development India's agricultural production has been rising, but it is still too slow to meet India's needs. Crop yields in India are among the lowest in the world. The possibility of raising farm output sharply through better crop yields is both a challenge and an asset on the agricultural front. Given irrigation—the life-blood of Indian agriculture—fertilizers, improved seeds and implements, and more and more educated and enterprising farmers to use improved methods, I am sure enormous increase in yields is possible. In fact, our agricultural programmes aim at providing these very things more rapidly and widely than in the past.

Heel of Achilles

Agriculture is often the Achilles Heel of most of the developing countries of the world. Under any form of agrarian organization, assuring high agricultural output has proved to be one of the most difficult of all production problems. India's struggle to achieve rapid economic transformation by peaceful democratic means will be won or lost in the rural areas because of the overwhelming importance and difficulty of rural problems. Patient persuasion and active help in the form of more extension services, more farm supplies, credit and marketing facilities, effective land reforms and fair

prices for agricultural produce have already begun to show results. Irrigation is being continuously expanded and more and more farmers are learning the use of 'wet' farming techniques. Eventually, the idea is to cover nearly half of all India's farm land—about 175 million acres, as compared to about 70 million acres irrigated at present. This will go a long way towards freeing Indian agriculture from the vagaries of the monsoon.

Raising agricultural output is then a process that will take time, and requires patience, efficient planning and organization. It also needs increasing support from the industrial sector for the supply of fertilizers, improved agricultural implements and for market for its surplus product. The importance of agriculture is so great to the whole scheme of economic development in the country, its relation so close to the hope of rural prosperity that in the current plan and in future plans, supreme efforts must and will be made to make it more productive and paying.

Industries for Rural Areas

In addition to more productive agriculture, rural prosperity needs some industries so that India's 74 million village families can keep pace with those in towns and cities. Prosperous agriculture alone cannot ensure adequate income for nearly 80 per cent of our people who live in rural areas. Moreover too many of our people are now dependent on agriculture. There is need to reduce this heavy dependence. This can be done chiefly through industry. Industry is a great modernising factor and opens the windows for new ideas. Its influence will be beneficial to agriculture and rural society as a whole. When we talk of industry in this context, it raises a number of questions of

wider import. What type of industry and how much of it can we take to rural area? How is it to be linked up with the overall plan of industrial development? What kind of location are we to choose for industries? How are the finances to be raised for developing industries?

Diversification Essential

In our overall schemes of industrial development both large-scale factory industry and cottage and handicraft industries have their roles to play. In order to produce complex things needed both for economic development and defence we need large-scale factory industry. But our handicrafts and village industries are important for diversifying the present lop-sided occupational structure of rural India. Taking a long-range view of things it appears necessary to evolve a balanced and efficient industrial structure. From the experience of industrialised western countries we know the disadvantages of concentrating industries in a few cities. Even in India until recently, the few industries that developed, grew around some big cities. Such concentration in a few big cities may have some initial advantage, but before long it gives rise to serious problems and disadvantages connected with public health, education, transport and other public services and facilities, including even water and electricity.

So we have to plan our industries in such a way as to avoid the grave social and economic evils associated with excessive concentration of industries in a few cities. In this context it is of interest to note that the 10 largest cities of India account for about five per cent of the total population, as compared with 20 per cent in Japan, 18 per cent in United Kingdom and 12 per

cent in the U.S.A. In this country we do not want such heavy concentration as in Japan or United Kingdom. At the same time we cannot make every village a centre of large-scale industry. So the ideal pattern appears to be a few hundred centres of industry well scattered all over the country. Such centres will serve as focal points of industrial influence. With such a pattern of industrial location it will be possible to minimise the gap between rural and urban parts of India. Together with such location, we must evolve a new type of industry—different from cottage and handicraft industries as well as large-scale factory industries—which can combine the efficiency of the latter with the employment potential of the former. The solution to the problem of underemployment and unemployment in our country, will to a large extent, depend upon the possibility of achieving this.

Accent on Savings

Whatever the pattern of our rural as also the entire economic development, we have to find the resources for our schemes of development. How do we find these? Historically speaking, in countries like United Kingdom, Germany, Japan etc., industrialisation was financed by squeezing resources out of the agricultural sector. We do not like to repeat that experience in India. But it is necessary and important that the agricultural sector pays at least for its own development. All development has to be financed by savings either of our own or of some one else's. Here comes the importance of rural savings campaign, taxation, compulsory deposit and the gold control order. While the first three, in so far as they apply to rural areas, are meant to create and mobilise savings in rural areas, the gold control measure is meant to pre-

vent savings from being spent on so unproductive an asset as gold. Buying gold is a disservice to the country at the present juncture, because almost all the gold that is bought and sold in this country is smuggled gold. It is a loss to the country and a gain to the smuggler.

There are many other aspects of rural economy such as cooperation, electrification, warehousing and marketing facilities which are being developed to transform rural India. Cooperation and electricity are the twin engines of rural progress. Both these are of vital importance for introducing and carrying forward an agrarian revolution as well to narrow the gap between the urban and rural cultures.

Three-tiered System

The vision of future rural India is not merely an economic one. As a democracy, it is necessary to provide opportunities for everybody, including the rural people, to play an active and direct role in planning and executing development schemes. The panchayat raj or 'rule of panchayats' is meant to provide this opportunity to the rural people. The panchayat raj constitutes a far-reaching change in the structure of local administration and rural development in our country. The chief purpose is to in-

volve all the people in rural areas to work for their own development. It consists of a three-tiered system of elected local bodies—the *panchayats* or village councils at the village level, a *panchayat samiti* at block level and a *zila parishad* at the district level. The great potentialities of panchayat raj lie in the fact that, under the guidance and supervision of the State Governments, the final responsibility for carrying out rural development will fall more and more on the people themselves through their elected representatives.

Democratic Participation

Although panchayats are an ancient institution in our country, it is a relatively new idea to charge them with responsibility for developing their villages for the common good of the village. Under the panchayat raj, if not every panchayat, at least panchayat samitis should learn to draw up local plans to fully exploit local resources and to find financial resources, at least in part, to execute their plans. It is this picture of rural India, with economic prosperity and democratic participation by all its people in rural institutions that Gandhiji held before us.

New Delhi
4 September 1963



EDUCATIONAL PROGRESS AND INDUSTRIALIZATION

K ARUNACHALAM

In 1951 the Planning Commission "redefined the aims, redesigned the method and content and reshaped the entire purpose of organised and systematic national education" Because of the dominant urban values in education, however, the economic development is tilted in favour of the urban sector. Rural areas lacking educational facilities also suffer from poverty and want. If Basic Education is introduced in rural areas on a large scale it would go a long way towards creating a climate for industrialization in the countryside

EDUCATION affects the economy in a number of ways, not only does it increase the flow of skills but also assists people to acquire new techniques. Moreover, it tends to destroy the traditional attitudes which impede progress, and it links knowledge with production. The economy in turn reacts on the educational system through science which has now grown more important in industry and so is taught increasingly in schools. On the one hand, therefore, education helps to strengthen the economy, for, it is an investment in manpower, on the other, it is becoming very expensive. As the national income grows, more can be spared for education. Our economy is moving more slowly than even that of our neighbours like Burma and Ceylon. We are short of engineers and scientists. We need hundreds and thousands of more qualified people very quickly.

Education is important, therefore, not only to help our children, to give them better lives, to improve the society in which we live, to enable our country to go forward paying its way and competing internationally, it is also

essential if we are to survive in a changing technical and scientific age. But education by itself is not enough. What matters is the kind and type of education. It must be geared to the world we live in, it must prepare people for life and for changes, help them to develop and become adaptable and it must reach them all.

Before Independence

Education in our country before the advent of freedom aimed at making out of the educated section of the Indian people recruits for conducting the British administration and for military defence. Clerks and soldiers with a small leaven of professional men made up the bulk of the "educated" who acted as the agents of the British in our country. Animated by the ideals and influences which inspired the Britisher in his own country these indigenous recruits and agents in India observed the same traditions and carried out the same policy, though in a more intensive form. Class rather than mass education became the rule or fashion and remains so in

many respects even to this day. Such a policy necessarily resulted in an over-emphasis on purely literary education and that too in a foreign language. The schools and colleges became so many factories for mass production of a standardised pattern.

On the eve of independence only 40 per cent of the children in the age group of 6 to 11 years and 10 per cent in the age group 11 to 17 years were attending school. There were disparities in the provision of educational facilities between different parts of the country, between different sections of the population and in particular between urban and rural areas.

Considerable wastage occurred at various stages of the educational system. Facilities for technical and vocational education were altogether inadequate. The proportion of teachers without training exceeds 41 per cent in primary schools and 46 per cent in secondary schools. There was considerable shortage of women teachers. Scales of pay and conditions of service for teachers were generally unsatisfactory and were in part responsible for low teaching standards.

In A Free Country

In such a system neither individual initiative was wanted nor independence encouraged. Imitation, repetition, routine without end or variation was the absolute rule. Such a state of affairs could not be continued for long in a free country. In an independent nation the people of the land have to shoulder direct responsibility and wield authority in the governance of the nation. A new educational policy and programme has thus got to be evolved and accepted throughout the country. Accordingly, the national Planning Commission in the year 1951 redefined

the aims, redesigned the method and content, and reshaped the entire purpose of organised and systematic national education.

Quantitative Development

In the following decade the annual expenditure of the Government on education increased from Rs 65 crores in 1950-51 to Rs 200 crores in 1959-60. The total expenditure which includes the contribution of local bodies, fees and other endowments registered an increase from Rs 114 crores to Rs 297 crores. The percentage of pupils in classes I to V to the total population in the age group 6 to 11 was only 42 per cent in 1950-51. This rose to 61 per cent in 1960-61. The target to be achieved at the end of the Third Plan is 76 per cent. By the end of the fourth plan 76 per cent of the children of school-going age are expected to be in school. It is true that there has been a considerable rise in the percentage at other levels of schooling also. Proportion for the age group 11 to 14 rose from 12 per cent to 28 per cent, for the age group 14 to 17 from 5 per cent to 15 per cent, for the age group 17 to 23 from 0.9 per cent to 2.4 per cent. But it is also a fact that the Constitutional Directive of free and compulsory education for all children upto 14 years of age still remains a pious wish.

In some states like Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Mysore, Punjab and Delhi, legislation for compulsory primary education has been enacted. Schemes have been drawn up for intensive enrolment in schools. Plans have been drawn up to train 1.5 million teachers.

The progress of primary, secondary and higher education in India during the period 1950-51 to 1959-60 is shown in tables 1, 2 and 3 respectively.

TABLE 1
PROGRESS OF PRIMARY EDUCATION IN INDIA 1950-60

Year	Number of recognised schools	Number of students on rolls	Number of teachers	Direct expenditure (Rs crores)
1950-51	2,09,671	1,82,93,967	5,37,918	36 49
1955-56	2,78,135	2,29,19,734	6,91,249	53 73
1956-57	2,87,298	2,39,22,567	7,10,139	58 48
1957-58	2,98,247	2,47,88,299	7,29,239	66 74
1958-59	3,01,564	2,43,72,181	6,95,280	63 64
1959-60	3,20,586	2,59,18,864	7,33,382	69 63

TABLE 2
PROGRESS OF SECONDARY EDUCATION IN INDIA 1950-60

Year	Number of schools	Number of students on rolls	Number of teachers	Direct expenditure (Rs crores)
1950-51	20,884	52,32,009	2,12,000	30 74
1955-56	32,568	85,26,509	3,38,188	53 02
1956-57	36,291	95,79,164	3,72,180	58 73
1957-58	39,654	1,06,21,499	4,06,768	67 21
1958-59	53,923	1,43,41,043	5,10,388	84 34
1959-60	57,863	1,57,06,200	5,61,959	95 65

TABLE 3

PROGRESS OF HIGHER EDUCATION IN INDIA 1950-60

Year	Univer sities	Boards of Educa tion	Research Institu tions	Special educa tion colleges	Profes- sional and Tech nical colleges	Arts and Science colleges	Number of students enrolled	Number of Teachers	Direct expendi- ture (Rs crores)
1950-51	27	7	18	92	208	498	4,03,519	24,453	17 68
1955-56	32	11	34	112	346	712	6,81,179	37,865	29 71
1956-57	33	12	41	128	399	773	7,50,195	42,135	33 54
1957-58	38	14	43	148	489	817	8,03,942	45,232	38 10
1958-59	40	13	42	168	542	878	8,76,312	52,180	43 92
1959-60	40	13	42	177	728	946	9,40,484	55,493	47 71

The need for expanding technical and vocational education was realised in the years following the second world war. In 1945 the All India Council for Technical Education was set up for advising the Central and State Governments on the schemes of development in technical and vocational education. Early in 1947 the Scientific Manpower Committee was given the task of assessing the requirements of scientific and technical personnel in relation to the post-war development programmes which were then under considera-

tion. A number of steps for increasing the facilities in this field were taken before the first five year plan. These included the establishment of the Indian Institute of Technology at Kharagpur, selection of 14 Technical Training Institutions for further development, the provision of research training scholarships and stipends for practical training and other schemes for the promotion of scientific and technical education and research. The results of the measures initiated in this period and those taken under the two

plans are reflected in the increase in the output of engineering and technological institutions during the period 1950-60 as shown in table 4

TABLE 4

PROGRESS OF ENGINEERING COLLEGES AND POLYTECHNICS 1950-66

Year	Degree course			Diploma course		
	No of Institutions	Admission capacity	Outturn	No of Institutions	Admission capacity	Outturn
1950-51	49	4,120	2,200	86	5,900	2,480
1955-56	65	5,890	4,020	114	10,480	4,500
1960-61	100	13,860	5,700	196	25,570	8,000
1965-66*	117	19,140	12,000	263	37,390	19,000

*Estimated

Qualitative Improvement

The importance of education for economic development can hardly be overestimated. There exists in the world of today, a practically perfect correlation between the educational level and economic development in the various countries. Even in our country because of the dominant urban values in education the economic development is tilted in favour of the urban side. The rural areas still lack educational facilities. They continue to be on the verge of poverty and misery. Wherever there is backwardness in education the economy also lags behind. In spite of our fifteen years of freedom and experience we are still groping in the dark and dissipate our energies and waste scanty national resources. The tendency to start too many schemes at the same time involves waste of efforts and the results achieved be-

come insignificant. As Vinobaji says "The single purpose of all education is that the whole nation should become skilful craftsmen and clean thinkers. But we subdivide this purpose into so many aspects—urban education, adult education, child education, nursery education, basic education, women's education, men's education, craft education, intellectual education, physical education and on top of all these there come literacy campaigns."

Vinobaji is of the opinion that our progress will certainly be retarded if we think of all these aspects separately. With a view to pleasing everybody the scanty resources are being distributed with the result that the most urgent and inescapable educational tasks have to be comparatively neglected. If our attention is distracted a little for this, a little for that, we shall find no real satisfac-

tion anywhere. We should keep a firm hold on the root and concentrate on seeing that it is properly attended to. The root is Basic Education. It includes craftsmanship, it includes development of intellect and it includes literacy also. It is an activity-centred curriculum wherein the process of learning is correlated with physical and social environment of the children. Education is imparted through socially useful productive activities like spinning and weaving, gardening, carpentry, leather work, bookcraft, domestic crafts, pottery, elementary engineering, etc. Even though Basic Education is now the nationally accepted pattern of educational system at the elementary level, the total number of schools that are of the basic type is only 29 per cent of the total number of elementary schools. The remaining continue to impart the same old Macaulayan type of bookish education. The percentage is expected to rise to 36 by the end of the third plan period. The reason for this tardiness is said to be the lack of resources available for education. But the main reason that is palpable is that the education administrators are not convinced of the relationship yet between the kind of education that is imparted and the industrial development of the nation. The old bureaucratic mentality persists. White collared values continue. However, we are told that in non-basic primary schools such important features of basic education as do not entail expenditure are being introduced. Orientation programmes for education to officers and primary school teachers are being implemented. The way in which these steps are taken, does not show that this revolutionary system of education is accepted with wholehearted appreciation and understanding. If only this system spreads widely in the country the five and a half lakhs of villages will be industrialised. They will be humming with activity driving out the demon

of underemployment and unemployment from our country.

All the teacher training institutions for elementary school teachers are being progressively converted into the basic type.

Significant changes are being carried out in the field of secondary education on the basis of the recommendations of the Secondary Education Commission with the aim of making secondary education a self-contained and complete stage upto the age of 17. Unique among them is the introduction of diversified system of education in which students could offer, in addition to a common core of studies, a group of three subjects from any one of the seven, namely, humanities, science, technology, commerce, agriculture, fine arts and home science.

At the university level also added emphasis is slowly being given to work experiences. Even though the recommendations of the University Education Commission on the rural universities were not accepted a few rural institutes have been started. More and more technical and vocational schools are being established.

Agricultural Education

A defect of the educational system is that there is a wide gap between the training of agricultural graduates and uneducated mass of agriculturists. The provision for a course in agriculture at the multipurpose high school or the bifurcated courses in the high schools under the present system is very inadequate for any practical purpose. It is desirable that a large number of post-basic schools with agriculture as the basic craft should be opened, where practical courses adapted to local conditions could be taught. The boys trained in these schools should be able to improve the farming practices on their fields and augment agricultural production. Deve-

lopment of agriculture is a *sine qua non* for the widespread development of industries in the country. For, agriculture is the base of most consumer goods' industries. When the national system of education is oriented this way it will be possible to industrialise India without dehumanising the individual.

We have made commendable progress in the matter of quantitative education. If the rapid expansion of technical education is not to reduce us to mere imitators and automations we must pay greater attention to the quality and appropriateness of the kind of

education. We should not sacrifice quality at the altar of quantity. We are anxious about the quality because we want to avoid the evils of industrialism and yet industrialise the country. If industrialisation takes place within a few metropolitan cities only as it is happening today the villages which are the very backbone of India, will continue to remain exploited and ultimately spell the ruin of the whole country. This can be avoided only by a properly oriented system of national education.

Madurai
2 August 1963

The thing that makes a man a citizen is thought. He must, therefore, so distribute the period of labour that he may have leisure for creative tasks. Obviously there is a physiological limit to the energy a man can afford to expend. But there is a civic limit to the amount the State can, for its own sake, permit him to expend. Those who devote their energies to attendance upon a machine become, as Aristotle saw, disqualified for the nobler tasks of life unless they have ample leisure to be other than the tenders of a machine. Certainly the frustration of personality involved, in the long hours of toil characteristic for instance, of the first part of the nineteenth century has been made obvious by inquiry into its results. Men and women came home from their daily toil incapable of thought and even of feeling. Their machines were their masters. There was no leisure in which they could find themselves. They knew only a life of endless toil. The right to reasonable hours of labour is the right to discover the land of the mind. It is the key to the intellectual heritage of the race.

Harold J. Laski *A Grammar of Politics*

PROGRAMME FOR INDUSTRIES IN RURAL AREAS

T N SINGH

The principal objective of the Rural Industries Programme is to raise the standard of living of rural population and create non-agricultural occupations in villages. The sponsors of the programme have underlined the need for adopting improved methods of production and using power where it is available. Besides providing facilities to the village, other positive steps will have to be taken by the State to achieve planned development of rural industries.

SOME important and significant issues were raised at the recent conference in Delhi of Chief Ministers and Ministers of Industries of various States on the Rural Industries Programme. In order to appreciate properly some of the important issues which figured at this conference, it may be desirable to analyse in some detail the principal objectives and assumptions of this new programme.

The principal objective of the programme is to raise the standard of living of the rural population and provide them with a variety of opportunities for productive activities at higher levels of income. It is proposed to create extensive opportunities for non-agricultural occupations in the rural areas. Improved methods of production or what has been described as 'intermediate technology' are to be adopted not only for processing of agricultural produce and raw materials but also for running small mechanised industries. In order that the people in these areas are able to operate better machines with a higher rate of production, a comprehensive programme for training them in new skills

and suitable methods of organisation and management work, is being undertaken.

Assumptions

Some of the assumptions of the Rural Industries Programme can be summarised as follows:

(a) In view of the very small holdings which will be further fragmented with the rapid growth of population it has become necessary to take off a large population from agricultural pursuits.

(b) A situation where there is continuing exodus of large number of people from the rural areas to urban areas in search of employment, may create tremendous social and economic problems which may well prove to be insoluble.

(c) It is possible to provide non-agricultural opportunities even in rural environments to large numbers of people, if the necessary facilities are provided and if the people are trained in requisite skills.

(d) Large amounts of valuable raw materials are going waste in rural areas and

if new and scientific techniques are introduced, they should provide new sources of employment to a sizable population

(c) Processing industries based on agricultural produce have a large scope and can compete successfully with large-scale units if suitable scientific methods are adopted

Availability of Power

The Prime Minister who inaugurated the conference laid great stress on the provision of necessary facilities, particularly electricity, which alone could provide opportunities to a large section of the rural population to take to pursuits other than agriculture. Some others also emphasised this point and went on to urge that without adequate supply of power it was not possible to launch any big programme of industrialising the rural areas. The point here arises that since it does not seem possible to electrify even a lakh or so villages in the near future, should one give up the entire programme of rural industrialisation till power becomes available in at least a lakh of villages. I am sure it was not the intention of the Prime Minister that pending availability of power we should bid good-bye to the rural industries programme. If that were so he would not have agreed to inaugurate the conference.

The sponsors of Rural Industries Programme have from the very beginning laid great stress on the need for adopting mechanised methods of production and using power where available. Many of the 46 projects which are in hand are located in places where power is available, though, there are some areas where facilities like power are lacking. Such a mixed bag is designed to give the workers an experience of the varying problems which one will

have to face in varying conditions in their attempt to increase the productive capacity in non-agricultural occupations in the rural areas.

Responsibility of State

There are a set of people who further believe that the State's duty is only to provide certain facilities and social overheads and the after things should be left to the free enterprise of the rural population. I am afraid, this theory will simply not work in conditions prevailing in the rural areas. We have not only to provide the necessary facilities of power, transport, communication and education in rural areas, we have even to take positive steps to engineer planned development of rural industries. What are commonly called the 'entrepreneurial' classes are unfortunately not only unfamiliar with rural problems and conditions, they would not simply think of venturing on such an effort.

Personally I attach very high importance to the development of necessary skills among our people in the rural areas and imparting technical knowledge to them. The average man in the villages possesses a natural skill to manipulate small gadgets. With proper training, in a very short time, I am confident, they can operate most power-driven small machines.

Workers

Before any positive steps can be taken it is necessary to undertake a techno-economic survey of the project areas. No systematic programme of rural industries is possible without adequate data about the resources, both in men and material of a project area. I think the success of the programme will depend very largely on the

correct judgment in regard to the choice of rural industries. Let us not forget that of equal importance for the success of the programme is the capacity of those responsible to apply themselves to the task sincerely, intelligently and with unremitting hard work.

Unconventional Approach

Economic surveys of most of the project areas have been completed, though I wish some of the surveys had been more thorough. After a detailed discussion with the project officers and the industry officers of various States, the Chairman of the Standing Committee and his colleagues are busy working out programmes for each project area. Many problems which were not thought of and many unexpected snags have to be faced. What I admire most about the approach to this programme of those responsible for its implementation is the unconventional and therefore refreshing manner in which they set about finding solutions to the problem raised. I have no illusions about the difficulties that we have to

face. It is almost like voyaging on an uncharted sea. In many cases we have to reconcile what apparently seems to be irreconcilable.

The sponsors of the programme would find not only inertia and opposition of those who usually do not relish new ideas, but even of a host of thinkers of modern and new way of life who scoff at things rural and things which do not look grandiose.

However, I think the readiness of the members of the Rural Industries Committees in the States and at the Centre and of the officers concerned to adopt even unconventional ways provided they are convinced of their efficacy and the steady and unostentatious manner in which they are devoting themselves to the task encourages me to believe that this programme should meet with success and probably show a new way to solve one of the most baffling problems of rural India.

New Delhi
19 August 1963

Our joys and sorrows are in a real sense historic events which, minute as they may be in the record of the political fabric, are collectively urgent in the test of its future. By a functional theory of rights is meant that we are given powers that we may so act as to add to the richness of our social heritage. We have rights, not that we may receive, but that we may do. Granted that we shall contribute unequally to the store of social well-being, it is yet imperative that the means of contribution shall be there.

Harold J. Laski *A Grammar of Politics*

PROBLEMS OF RURAL CREDIT

B MUKERJI

An integrated, decentralised but efficient banking system wholly dedicated to the cause of developing rural areas on a decentralised basis is a vital necessity. With the introduction of panchayati raj consideration will have to be given to the setting up of 'community banks' having responsibility of serving as bankers to panchayati raj institutions and assisting in the economic development of the rural communities.

MODERN banking facilities are hardly available in the vast rural areas of our country. This is due to the fact that banking even now remains largely concentrated in the industrially and commercially developed regions. But to talk of the problem of rural credit is to refer to the much more difficult problem of making credit available to the agriculturists for their agricultural operations and to the rural sector of the economy generally. The importance of this problem would be obvious if account is taken of the facts that nearly 80 per cent of our people live in the villages, nearly three quarters of them are dependent on agriculture, and that agricultural production contributes to nearly half the annual gross national product. In a way, therefore, to talk of the problem of rural credit is to talk of institutional finance for agricultural production.

Though agriculture is both an art and a way of life, yet it remains a business and like other businesses cannot be carried on unless funds are available for the maintenance, replacement and improvement of its capital equipment, and for the working expenses of its production. The need for such funds

becomes all the greater when, as in our case, agriculture has to be greatly improved. New and improved methods of farming have to be adopted, involving the use of better farm implements, better seeds, more fertilisers and irrigation water. Even for subsistence farming credit is necessary.

Agriculture differs from most other industries in several important ways and it is from these differences that the special difficulties of providing credit for agriculture mainly arise. Unlike big industries, which concentrate in certain areas and take the form of public companies with limited liability and have extensive capital resources and salable assets, the overwhelming mass of agricultural production is in the hands of individuals or families, conducting relatively small independent enterprises with very limited capital and equipment. It is this very large number of producing units, the limited capital resources of each producer, and the personal nature of his enterprise that cause many of the difficulties inherent in the provisioning of agricultural credit. While the personal nature of the enterprise and the limited means of the producer make it more important for a lending institution

to keep greater personal contact with the borrower, because of the numbers involved and the persons being distributed over vast areas of the country, some even difficult to reach, maintaining such personal contact becomes almost impossible

Another special feature of agriculture is its long production period. This restricts the use of commercial banks as direct sources of credit to ordinary farmers, as banks require quick turnover of their money. Then there is the question of long-term financing for purchase of land, of cattle or machinery or for making land improvements. To the ordinary commercial banker financing of agriculture is generally unattractive because the cost of administration is always heavy and the risks involved higher than in other businesses.

Administrative Problem

Any system of financing the farmer has to take care of all his credit requirements, short-term, medium and long-term, production credit and personal credit, and assess the overall risks involved to ensure that the farmer's total indebtedness is not beyond his capacity to bear and not such as would cripple his productive capacity altogether and make him permanently indebted. Not only will the needs of individual farmers vary, there will be considerable difficulty in assessing individual requirements. To make necessary funds available to a very large number of farmers and to have to assess their requirements separately is the main problem of agricultural credit, and this is a problem of administration more than of economics.

Thus it is that the cooperative channel of financing has come to be regarded as the

only feasible one. The experience of many other countries has already proved this to be correct. The cooperative being located in the village itself or near at hand can keep in close touch with all the borrowers. The members of the cooperative have mutual knowledge of each other and can vouch for each other's character, capabilities and requirements and so the society can lend without undue risk and supervise the use of the loans without much difficulty. Being autonomous in its working the cooperative society can mould its policies and practices to suit the different conditions of different regions or of individual borrowers. But above all, the cooperative approach seeks to inculcate in the members the habits of self-help, thrift and mutual cooperation, and promotes in the community social cohesion. It faces realistically the fact that, to a very large extent, the people in the rural areas will have to depend on themselves and on their own resources, and has the faith that cooperatively they can do much more than they can do individually.

Socialist Pattern of Society

The cooperative was introduced in this country around the turn of this century. But during the British regime it made very little progress. In our five year plans cooperation has been accorded a very important place both because of its practical significance and because it is in accord with the basic policies of the country of promoting a socialist pattern of society and a democratic welfare state. In the Second Five Year Plan it was said, "Economic development along democratic lines offers a vast field for the application of cooperation in its infinitely varying forms. Our socialist pattern of society implies the creation of a large number of decentralised units both in agriculture and

industry" "The cooperative form of organisation has advantages which neither the system of private enterprise nor of State ownership can match. In particular, it offers the means to achieve results valuable to the community by drawing equally upon incentives which are social and incentives which are individual."

Uneven Progress

The progress already achieved is significant. The number of primary agricultural societies has increased from 1,05,000 in 1950-51 to 2,15,000 in 1961-62. Their membership has grown from 44.08 lakhs to 195.06 lakhs and working capital from Rs. 37.25 crores to Rs. 325.25 crores. While these are impressive figures for the whole country, the progress is not uniform all over the country and only the fringe of the problem has been touched. While the progress in a few parts of the country has been encouraging that in several other parts has been most disappointing. Much thinking, planning and effort has gone into the endeavour to develop the cooperative sector, but I doubt whether it can be confidently said that we have even reached the high-road that will lead to success in achieving our declared goal. I will not discuss in any details the various aspects of our cooperative programme that continue to remain weak, nor the defects that persist in the implementation of the programme, nor the other reasons that continue to hamper progress. These have been considered by many committees, working groups, etc., and voluminous reports have been published to make all this common knowledge. I shall, therefore, refer to other aspects of the question

Educating the Villager

It is necessary to realise that the task is a very difficult one. It involves educating,

organising and motivating hundreds of thousands of rural people into new beliefs and ideas, to function intelligently and actively in new democratic institutions, and to apply themselves to new tasks of economic and social welfare. To bring about such a change over a vast country and in respect of people largely illiterate and tradition-dominated will be complicated, laborious and time-taking. But what is most important is that the cooperative activities are closely and effectively linked with the promotion of the economic and social welfare of the rural people and that this is demonstrably so and carries conviction with those people.

The cooperative movement will have little chance of success if there is not adequate success in improving agriculture and in promoting rural industrialisation, though success in the latter field may be dependent, to some extent, on success in promoting cooperation. Sound and good planning and efficient implementation of the plans will be needed. Agriculture alone can never provide employment to the entire labour force of the rural areas unless it means employment at subsistence and even below subsistence level. If rural industrialisation does not provide other avenues of employment in the rural areas, much of the labour force from there must continue to migrate to areas of industrial concentration and thus create both social and economic problems.

But to be able to achieve the twin purposes of providing employment or fuller employment to the surplus labour force and to add to the production of wealth in the rural areas to secure for the rural people a rising standard of living above the level that can be achieved only on the basis of an agricultural economy, however improved it may be, it is necessary that the programme of rural

industrialisation should be well-planned and co-ordinated with the plan of agricultural improvement as well as with the plan for large-scale industrial development

I am talking of rural industrialisation and not of rural industries or what are more commonly known as village industries. While the latter may have to be rehabilitated and kept going for some time in the absence of something better, they cannot be preserved at the low level of technology for all time to come. There has been much sentimental, unsound and often confused thinking and talk in recent years about the place of traditional village industries and the need to preserve them as they are. There could be no doubt that the success of any programme of rural industrialisation must depend on the selection of industries which are economically viable or can be made so fairly quickly and which are capable of adopting progressively improving technology.

Viewed in its true perspective the objective of rural industrialisation, to quote the words of Professor Gadgil, should be, "Industrialisation of the country as widely dispersed, at as small a scale, with as high an employment potential as is compatible with an efficient technique and the requirements of the development process". When I talk of agricultural development in this context I am thinking of agriculture developing eventually into an efficient commercial business. Planned on a decentralised regional basis it should be possible to bring about a great deal of mutual assistance and interdependence between agricultural development and industrial development in the rural areas. It is also possible to plan for a degree of mutual assistance and interdependence between the small-scale industries

that will be dispersed in the rural areas and the large industries that would be concentrated in the industrialised belts of the country.

Making Rural Economy Creditworthy

Provisioning of credit for rural industrialisation will have to face difficulties of a somewhat similar nature as for agricultural development, and more or less, for similar reasons. The credit rating in the case of both purposes will be low, judged by usual banking standards. But in both cases the needed credit will have to be found to improve the creditworthiness. This shows the complexity of the situation, but also the vital importance of adopting a sound plan of economic improvement of the rural areas which has the promise of making that economy viable and creditworthy, for an ever-increasing level of investment, taking into account all relevant factors, e.g., the growing population, the inadequacy of the total resources, the lack of technical knowledge and managerial ability in the rural areas, the limited market that there will be in the beginning, etc. The problem of rural credit is only one side of the coin, the other side is the problem of making the rural economy creditworthy. Only together can these two problems be solved.

Decentralization

The question may be asked how can the kind of development of the rural areas that I am talking about be achieved. My answer is that this will not be achieved unless there is an overall policy of promoting decentralised socio-economic communities within the framework of a Democratic National Government and a National Plan of development. A centralised approach will be

doomed to failure. I will not go here into the question of how decentralised planning for regional development is fully compatible with an overall, integrated National Plan. The point need not be argued since, as I see it, we have already accepted the policy of decentralisation by the adoption of a far-reaching and radical concept of panchayat raj and by assigning a very large and important place to the cooperative form of organisation in our development programme.

The development of the right kind of local leadership will be a matter of vital importance for the success of the development programme and only a far-reaching decentralised approach will promote such leadership. The scheme of panchayat raj will succeed only if the principle of decentralisation which it incorporates applies equally to the political, social and economic spheres. To tell the village masses, who live in utter poverty, that the panchayat raj institutions are their institutions and are being given wide functions will not impress them unless they find that these authorities are able effectively to deal with their economic problems. They should be able to command adequate financial resources for this purpose. They will have to look after the improvement of agriculture in the village and the promotion of industries that will provide employment to the unemployed or the underemployed, and not only take care of the civic functions commonly attended to by local authorities. I even visualise zilla parishads and panchayat samitis starting industries which will be publicly owned, just as State Governments and the Central Government have public undertakings, in

order to improve the economic life of the village people.

Cooperative Basis

No doubt these industries will have to be of the kind which can be developed largely on the basis of local effort and within the capacity of the local authorities to manage. The fruition of an idea like this may take time, but such must be our goal. In addition there will be many industries organised on a cooperative basis. The social objectives of our planning require that the development of the rural areas, whether agriculturally or industrially, should be organised on cooperative lines as far as possible. If the rural people have to promote their own industries, based as these must be very largely on their own effort and local resources, there seems to be no other alternative than to promote these largely on a cooperative basis. But it will be wrong to assume that the cooperative form of organisation necessarily goes only with the backward economy of rural areas, with technology of a low order, and marketing based on the idea of self-sufficiency of the village. It is possible, and this has been demonstrated in many advanced countries, to organise on a cooperative basis efficient production, sound business management and a steadily improving technology.

Raising Resources Locally

Now I come to the very important question of how adequate financial resources can be made available for the kind of rural development that I have visualised. Space does not permit going into the details of this question. The general principle, which I think is of some importance and, in my opinion, has considerable validity, is that to a very large extent the resources needed for

the development of the rural areas on the pattern indicated by me should be raised in the rural areas alone. This is a principle which has a long-term validity, but it does not mean that in the short run outside assistance would not be needed. Such outside assistance is being given by allocations under the five year plans, particularly, under the programme of community development, the programmes for the development of cooperation, agriculture, village industries, etc.

I visualise that when the panchayati raj institutions are fully developed they should be able to raise significant amounts by taxation. Not all these taxes need be imposed or collected by them. Some, as for example, the land revenue, may remain a State tax, but the panchayati raj institutions would get their share of the proceeds. Other taxes may also come in the category of distributable taxes. But the list of taxes which the panchayati raj institutions will themselves impose and collect should go on increasing and should bring them more and more revenue. Then there should be loans given to them by the State Government. They should also be able to borrow from the market themselves. With the strengthening of the cooperative movement and its banking channels, more and more funds will be raised by the cooperative sector and become available for development purposes, i.e., by raising of share capital of the cooperative institutions, building up of reserves and borrowings from outside sources.

Common Banking Structure

For carrying out their development responsibilities of the kind that I visualise they should ultimately have, the panchayati raj institutions will need banking services which the cooperative channels will not be able to

provide. Our cooperative movement has so far been geared to meet primarily the requirements of agricultural development. Even with a great deal of rural industrialisation agriculture will still remain the predominant activity of the rural communities. I doubt, therefore, that the cooperative banking channels will be able to help much in the development of industries in the rural areas. Their bias is bound to remain in favour of agriculture. The panchayati raj institutions will in course of time need a variety of banking services, as for example, for managing their growing cash transactions, help for raising loans for capital and public works, working capital for their industries etc. We must also bear in mind that as our agriculture gets commercialised, as it must, to provide a higher standard of living to the people engaged in it and also to sustain a development programme of growing magnitude, it would need very substantial capital investments. I feel that in our country a mixture of the approaches of the cooperative and commercial banks in financing agriculture will be to agriculture's advantage. In the ultimate picture it may be an advantage to have a common banking structure to meet the requirements of rural development based on the promotion of both agriculture and rural industrialisation.

Community Banks

There would be need for a 'community bank' having the special responsibility of serving as bankers to the panchayati raj institutions and of assisting in the economic development of the local communities. In suggesting this I am, of course, presuming that the panchayati raj institutions will develop into decentralised local authorities of the kind I have visualised. It is futile to expect that branches of big commercial

banks can play such a role. It is also difficult to conceive that a cooperative society or bank can play such a comprehensive role. In the 'community bank' that I am suggesting there should be combined the good and strong features of both cooperative and commercial banking. They will have to function on a highly decentralised basis and in close alliance with the local authorities. They could be brought into being by the participation of a number of financial institutions, such as the State Bank of India, State Financial Corporations, Cooperative Banks and other commercial banks, in the same manner as some of the developmental financing institutions have been created. There is no reason why such small banks cannot function efficiently if a good system for their control and guidance by experienced institutions like the State Bank of India and the Reserve Bank is devised.

Small Banks in U. S. A

I must confess that I have not given enough thought to this idea of a "community bank" to be able to elaborate it, but I do feel that the idea is worth exploring. In the history of banking of U. S. A., during the early period of the country's development when the population was moving from the East to the West and opening up new areas, small banks as community banks played a very valuable role. They grew and progressed with the newly established communities and helped those communities to progress. Their sense of loyalty and obligation towards the community in which they functioned was strong. There are lessons for us to learn from this history of American

banking, both good and bad. My main point is that in developing our rural areas on a decentralised basis and through the promotion of an agro-industrial economy we would need an integrated, decentralised, but efficient banking service wholly dedicated to the cause of this development. Its policies, functions and procedures have to be in harmony with the requirements of the region and the economy it has to serve.

A corollary of this idea is that this banking structure should be assured of the bulk of the savings and business of the community it has to serve. For, as I have said, the rural areas have to develop very largely on the basis of their own resources. Today, there is growing competition between commercial banks, cooperative banks, Government's small savings drives for the savings of the people. Commercial banks are opening branches in the countryside. Some kind of allocation of fields of operation between these agencies may have to be thought out if the concept of decentralisation is to ultimately succeed in a large way. It should not at all be difficult to arrange for a great deal of collaboration between the different financial institutions operating in the countryside, which collaboration will be to the advantage of all of them. The need for such collaboration and understanding between the Reserve Bank, the commercial banks, the development banks and the cooperative banks is already becoming apparent under the impact of our economic development.

Bombay
6 September 1963



IMPACT OF KHADI ON OUR ECONOMY AND SOCIAL ORDER

ARUN CHANDRA GUHA

The impact of the programme of khadi and village industries on our social and economic conditions has to be judged by the extent to which it succeeds in giving relief to the poorest sections of the community

THE programme of khadi and village industries has come to Government of India directly as a legacy of the Father of the Nation. Throughout the period of struggle for independence under the leadership of Mahatma Gandhi, this programme played a very important role. Every worker was pledged to the creed of khadi and village industries. So the Government as a whole or the persons holding responsible positions in the Government are emotionally attached and committed to this programme. But it would not be correct to say that this emotional attachment is the only reason for our Government to accept the policy of promoting village industries. India is a poor country. Before the Second World War, the per capita income of India was a little more than Rs. 100 per annum. Even now, vast masses of people are unemployed or very much underemployed. It is an obligation for any Government to find some employment to the unemployed or underemployed masses and thereby increase their per capita income. There is some assessment of the urban unemployed through the Employment Exchange, but the position of employment in the rural area is anybody's guess. Yet it is known that a vast

portion of the rural people is only partially employed—for about 150 days a year only.

Time for Assessment

That is the economic and social reason for drafting this programme of khadi and village industries. From the beginning of our independent nationhood, we have been working this programme with the idea of providing an alternative source of employment for the rural unemployed and partially employed. After pursuing the programme for about 16 years, it may be appropriate to make an assessment of the impact of the programme on our social and economic structure. It is seriously contended that real income of the lowest stratum of the people has not increased during the last 15 or 16 years, their income might have increased in terms of money but not in terms of goods and services enjoyed by them. It should now be examined if this programme has made any contribution in changing the pattern of our rural economic order.

Performance of Khadi Industry

From the latest annual report (1961-62) of the Khadi and Village Industries Commission, we find about 17 lakhs of persons

are engaged in khadi work and most of them are part-time workers. The Commission has distributed a little over Rs. 17 crores to these 17 lakhs of men, so the per capita earning of these men could be just about Rs. 100 per annum, or Rs. 8.33 per month. For a poor country where the poorest section of the people have an earning of only about Rs. 8 to 10 per month, this addition of another Rs. 8 is not a negligible figure. On the basis of the calculation made in the Third Plan report the total number of unemployed in the rural areas would be a little above 1.75 crores (including a little over 1.15 crores of new entrants into the employment market and about 60 lakhs from the backlog of the Second Plan). If the khadi programme has given part-time employment and an average remuneration of about Rs. 100 per head per year to 17 lakhs of men, it has helped about 10 per cent of the rural unemployed. This is not a very mean performance. Of course, this calculation has not taken into consideration the vast number of underemployed.

The entire khadi programme has on its credit side the sale of a little over Rs. 17 crores for the year 1961-62 and in that very year, the Commission disbursed in grants and loans about Rs. 18 crores. On reading the report one feels surprised that the Commission disbursed a sum of Rs. 17.93 crores for the year 1961-62, the whole programme also produced khadi of the value of Rs. 17.54 crores. One may be tempted to presume that the entire amount was a sort of gratuitous relief by the State to the spinners and weavers engaged in khadi programme. But I think this is not a quite correct assessment, the disbursement every year does not all come from the Government. A portion of it is the earning of the Khadi and Village Industries

Commission which gets the sale price of khadi, and a portion of it has come as part repayment of loans advanced. In this regard, one disquieting feature is the ever-increasing amount of outstanding of the loans—now standing at Rs. 35.58 crores. It may be questioned if the entire amount will ever be realised.

State Boards

Two years ago, the Khadi and Village Industries Commission's work was examined by the Estimates Committee of Parliament. It was noted there that the Commission disbursed over Rs. 22 crores to the State Boards but utilisation certificates were received only for Rs. 1.47 crores. So from the point of view of audit and accounting, it may be argued that an amount of about Rs. 21 crores still remained unaccounted for. We may hope that the State Boards have been now functioning properly in the matter of accounting and audit formalities. It is our sad experience that while the Commission itself wants to work in a sincere and earnest manner, the State Boards often do not show the same mental attitude. Often politics plays a dominant role in the formation and working of the State Boards. It might not have been a wise decision of the Commission to delegate the working of the programme to the State Boards, leaving for itself only some authority for disbursing money and an ineffective supervision.

We are afraid that the Commission often takes up a very diffused programme. Spinning, weaving and the sale of khadi form the main programme for the khadi section of the Commission, and now it has decided to leave the production and sales of khadi to the State Boards. But we are not sure if it was wise on its part to enter into

the field of experiment and research in the production of cotton. That should have been left to the appropriate authorities—the Central Cotton Committee and the Ministry of Agriculture. On that analogy, the Commission should have reason to go into far wider fields of agricultural experiment and research. For all this there are specialised bodies

Power in Cottage Industries

Use of power for cottage industries has been under discussion for a long time. As far as we have been able to understand the mind of Gandhiji in this respect, he would have had no objection to that as he had advocated the use of any mechanical device to lighten the labour of the primary producers. The vital point on which he insisted very much was that the worker must be the owner of the means of production and of the fruits of his labour and that he must not be converted into a bond-slave. In preference to hand sewing, he had no objection to take the sewing machine as that would very much relieve the hard and tedious labour of the women at home. Yet the Commission had much hesitation in accepting the use of power in village industries. A committee was set up to consider the question of power being used for cottage industries. The Committee recommended the use of power, but we find from the report that the Commission is still hesitating and is trying to “take measures for the production or generation of power on a decentralised basis.”

Generation of Power

The Commission's idea is “the decentralised production of power from locally available material should be treated as a

primary village industry.” We are afraid the Commission would be treading into difficult terrain. For the production of power the Government machinery, almost the monopoly machinery now is the Ministry of Irrigation and Power and its subordinate agents. This is a specialised subject and every attempt should be made to produce power at a cheaper price. The bigger the unit, the less is expected to be the cost of production of power.

One of the handicaps from which cottage industries suffer is that their cost of production is higher than that of factory-produced articles. And one of the means of reducing the cost of production is the use of cheap power. Now if the Commission's idea of decentralised production of power is given effect to, that would mean that the cottage industries will have to bear a higher charge for electricity. Moreover, if rural industries are to wait for the decentralised production of power, we apprehend they may have to wait for an indefinitely long period. The Commission has been considering the utilisation of cow-dung gas and solar energy. We have yet to know—in spite of long years of publicity about these—when these may be of any real service to the rural people. A difference has to be made between demonstration-production and commercial production.

Unfounded Fears

It is no use being too sensitive or doctrinaire in matters affecting the economic life of the nation or even of the poorer section of the nation. The Commission should not feel that power of a big generating unit may pollute the cottage industries if introduced there. The first consideration in this matter should be reducing physical

strain and reducing the cost of production, thereby giving the village worker some relief from the strain and some more money. Human labour should be given its proper dignity and should not be treated as labour of the beast of burden.

What we have said about khadi would apply equally to almost all other village industries. We think that for handmade paper power is more necessary than for khadi, in soap production also power may give better result. It may be apprehended that introduction of power may result in reducing the employment potentiality of the programme. But textiles and other consumers' goods being rather in short supply, no such fear is justified. Further, the introduction of four or six spindle charkha with gear and ball bearing should also have been avoided—on the analogy of objection to electricity.

Ambar Charkha

The Commission has made several experiments about improving the charkha. It would be worth while to assess the future fate of the ambar charkha programme. About four lakh ambar charkhas have been distributed, about two lakhs of ambar charkhas are now lying idle. The Commission is now thinking of turning them into six-spindle charkhas and also improving their mechanism to make them lighter and easier to ply. That would give greater output and higher remuneration. Before undertaking the programme of remodelling this old ambar charkha it is better to see whether, ultimately, it would be cheaper to produce a better type of charkha than to remodel this old ambar charkha. Voluntary certified organisations have been asked to

take over the old ambar charkhas, but they have all been hesitating to do so.

Ambar charkha was introduced with great optimism as a better type of charkha with higher productivity and more remunerative to the spinners. There is wide scope even now to have a charkha with gear and ball-bearing and lighter to ply. If necessary such a charkha should be run on power. That would give us a sort of a spinning machine on the cottage industry scale. On the weaving side, there is yet the resistance to accept power. We appreciate that powerloom instead of handloom may mean reduction in the employment potentialities of the programme, but we think that in view of the not-too-abundant supply of textiles, such a fear is not fully justified.

Employment, Earnings and Price

While employment is an important aspect, another equally important aspect is to ensure a proper remuneration to the men engaged. It may be considered by the Commission whether the improved spinning machine to be worked with power, together with powerloom, cannot be taken as a basis of cottage industry. We should not base our programme on the assumption that the volume of unemployment will not be relieved in the foreseeable future. The question of supply of consumers' goods at a fair price is also a very important issue at the moment. The programme of khadi and village industries should not become an impediment to that.

It should be remembered that the economy of India is passing through a crisis. The crisis is one of high cost of production and inadequate supply of goods, both leading to higher price and, consequently, to higher cost of living. Among the reasons

for the higher cost of production, one is the necessity of finding employment for the unemployed or underemployed. For that we have the programme of labour-oriented industries as against capital-oriented industries. Capital-oriented industries can supply goods at a cheaper cost, but labour-oriented industries will naturally mean higher cost.

Economically Viable Programme

During the Second Plan, the Government spent a little over Rs 87 crores for khadi and village industries, out of which Rs 68.68 crores alone went for khadi, and the provision in the Third Plan period is Rs 92 crores for khadi and village industries. This is a big investment. And the value of the products out of these investments may be just of the same amount, as we find from the report of the Commission for consecutive years. This makes an impact on the total cost of production of the other articles as also on the taxation policy of the Government. We should also remember that the old generation of leaders who were pledged to the creed of khadi is passing away, the new men would not have that emotional attachment to this programme. So it is time that the programme is placed on the basis of economic viability.

Khadi and village industries as we have stated earlier have been taken up by the Government not only as a sacred legacy of the Father of the Nation but also as a measure for improving the economic condition of the poorest section of the people. It is to be judged now how far it has been able to give relief to the poorest commu-

nity of the nation. One may be tempted to say that the impact of khadi and village industries on the social and economic life, not only of the whole nation but even of the poorest section, is not yet so appreciable as to justify an expenditure of about Rs 92 crores in five years of the Third Plan. Advocates of big industries can claim that with Rs 92 crores the Government might have established some more cotton mills and factories for producing consumer goods. The present scarcity of textile and other consumer goods has led to higher prices. The spiral of high prices of consumers' goods is a serious problem for the Government. To relieve the scarcity and thereby to reduce the prices of consumers' goods, people may argue that the Government should consider whether they should lock up the huge amount in programmes where production would be comparatively low, and would not help in removing the scarcity of consumers' goods by making more fruitful investment.

The Commission and the advocates of khadi and village industries will have to satisfy themselves that these investments will really help in removing substantially the scarcity of consumers' goods, particularly of textile goods—at least for the rural consumers. Economic viability not only of the industries set up but also of the programme should receive more attention. This is a programme for the benefit of the poorest sections of our people, it should be our concern to ensure that these men live consistently with the developing aspirations of the people.

New Delhi
7 September 1963



WHITHER KHADI?

DHWAJA PRASAD SAHU

For securing expansion of khadi work on a large scale popular support will have to be mobilised. This can be achieved by enthusing people to shoulder responsibility for its development. The new proposal for free weaving of khadi and the gram ekaï programme provide an opportunity to the workers to advance in this direction.

A REPORT of the activities of the Gandhi Ashram of Akbarpur (in Faizabad district of Uttar Pradesh) submitted to the annual meeting of the ashram held last month, showed that achievements in respect of production and sale of the ashram during last year had fulfilled the expectations. In spite of this, there was no programme of expansion planned for the coming year. This state of affairs obtains in respect of khadi institutions all over the country. The old major institutions have reached the limit of their capacity and are not willing to expand their work. The new institutions are short of efficient workers as a result of which they are not able to take up programmes for expanding their work. Besides, the usual difficulties about marketing are also there. Though there has been good progress in the production of *kambals* which are being produced for supply to the armed forces, the production of cotton khadi is increasing only at a snail's pace in some centres. It would not, therefore, be wrong to say that khadi production has reached a stage of stagnation. This is a state of affairs which should cause anxiety about the future of khadi. It is said that anyone whose growth is stunted is not likely to

survive. Are the prospects for khadi equally depressing?

Rebate, No Solution

Some of the responsible persons connected with the khadi institutions hold the view that the present rate of rebate of 25 naye paise per rupee on khadi sold should be gradually increased so that the cost of khadi would be reduced and its production could be increased. It is a point for consideration whether the khadi industry could be stabilised by increasing the quantum of rebate when khadi is twice or thrice as costly as—or even costlier than—mill cloth, and whether the Government could be induced to make available the necessary finances. I feel that the foundations of khadi industry cannot be strengthened by increasing the rate of rebate—which itself is not feasible—unless the whole problem is viewed from a fundamental perspective. Since the survival of khadi itself is at stake, those interested in the survival and development of khadi should give serious consideration to the problem and chalk out some firm and revolutionary steps for imparting strength to the khadi industry.

Acharya Vinoba Bhave is not satisfied with the present slow pace of khadi work

and he holds the view that khadi cannot survive unless some revolutionary steps are taken. It is, therefore, that he is advising the khadi institutions to forgo aid for khadi industry in the form of rebate. Khadi can survive only if it is based on the willingness of the people to make sacrifices for their neighbours. At the meeting of the Khadi and Village Industries Board held in Nabadwip in West Bengal khadi workers showed their readiness to give up aid in the form of rebate if it was substituted by free service for weaving handspun yarn. Vinobaji accepted this as a compromise proposal. He believes that khadi can make sufficient progress by the new arrangement and khadi work can be broadbased by this changeover which would also strengthen the foundation of the khadi industry.

At present the khadi industry is neither self-sustaining nor does it have popular support. It is surviving because it is associated with the name of Gandhiji and as a result of the benevolence of the present Government. For securing expansion of khadi on a wide scale, we will have to mobilise popular support. Khadi institutions will have to change their present form and methods of work. Those in charge of khadi institutions should take steps to hand over charge of the work which is being carried on by the institutions, to the people. The new facility of free weaving for khadi provides opportunity to the workers to strive for the fulfilment of this objective.

Tasks for Workers

At present hundreds of khadi institutions are carrying on khadi work in nearly a lakh of villages through some 30,000 to 35,000 workers throughout the country. I think that 20,000 to 25,000 of these workers can take up work relating to the intensive

development of handspinning in units with a population of 5,000 each, and encourage villagers to consume a major portion of the khadi produced in the village by explaining to them the philosophy of khadi. It would be necessary to convince the gram panchayat that it is its responsibility to provide work to the unemployed in the village. Khadi workers should address themselves to the task of setting up institutions at the panchayat level which should be run by the local population. Many of the 25,000 workers to whom I have referred earlier may be residents of these villages. They can take up the responsibility of organising the work on these lines in their areas and set an example to the villages in the neighbourhood and create a favourable climate for organising work along similar lines in them. Other effective methods of rousing popular enthusiasm and mobilising it can be found out. I have only shown lines along which we can proceed.

Targets

The gram ekaï programme formulated by the Khadi and Village Industries Commission is a step in this direction. Though the targets set up for gram ekais are quite high and will take quite some time for fulfilment, the target fixed for the initial period is consumption of only a square yard of khadi per head of the population living in the ekaï. It is true that the new ekais would need some time to achieve even this modest target. Every khadi institution should strive for the fulfilment of this modest target in villages where its production centres are located and inspire the local population to shoulder the responsibility for it.

A heavy responsibility rests on the institutions under the new scheme of free

weaving of khadi and they will have to make arrangements for weaving of khadi in all places wherever spinning is carried on. This is indeed a difficult task though not certainly an impossible one. This should be achieved easily in places where services of professional weavers are available. In other places new persons will have to be trained in the technique of weaving. Since our experience is that a number of persons who take training in weaving, do not later on take to it to earn their living, many persons are doubtful about the effectiveness of the programme of training new weavers. It should, however, be remembered that a

large number of people who took training in weaving in the past have become good weavers and are earning their living through weaving. We have hence to choose persons who are really interested in taking up this work. Imposition of work on unwilling persons will not prove beneficial. The fact that thousands of ambar charkhas are lying idle bears testimony to this. In the end we must remember that though our path is strewn with difficulties nothing can come in the way of a dedicated person striving relentlessly to attain his objective.

Patna
20 August 1963

The prescriptions of the State are never final prescriptions. The guide to our conduct is not the voice of authority, save in so far as the results of authority go to the realisation of ideal right. A State must give to men their due as men before it can demand, at least with justice, their loyalty. And it may be urged that in a period when active citizenship is coincident, broadly speaking, with the adult population, the test to which the State is submitted becomes more serious than at any previous time. Men who are granted political power sooner or later become insistent that the result of power be rights. They will seek the institutions through which the substance of rights can be best secured. They will either universalise privilege, or else abolish it. They will insist that liberty and equality are inevitable corollaries of a democratic system. They will seek the diffusion of those notions through the whole fabric of the community, at least to the point where the power of the State is placed with approximate fairness at the disposal of all. In the end, resistance to such demands is difficult, for, as Acton pointed out, there is a reserve of latent power in the people which few minorities have either the strength or the cohesion to overcome. The State, therefore, which seeks to survive must continually transform itself to the demands of men who have an equal claim upon that common welfare it is its ideal purpose to promote.

Harold J. Laski, *A Grammar of Politics*

FUTURE OF KHADI

R K PATIL

Khadi cannot survive unless it becomes an integral part of the life of the community. Commercial khadi has a very limited role to play.

WHAT is the objective behind khadi? Is it to be utilised as an instrument of ushering in a new society with new values of life, or is it to provide employment, rather residuary employment, to those who need it? The absence of a clear formulation in this respect is responsible for some confusion and also difference of opinion amongst khadi workers. When driven to a corner in argument some of them say that their objective is the latter, and let the Akhil Bharat Sarva Seva Sangh or some other institution take upon itself the responsibility of ushering in the former. But those who argue like this fail to realise that, from this angle they have no claim to exploit Gandhiji's name and associate it with the khadi of this description. For whatever may have been Gandhiji's approach in the twenties, when khadi work was first started, in the forties, when he gave a new orientation to khadi work, he was very clear on the objectives of khadi. When he said "spin, spin knowingly, and those who spin should wear khadi, and those who wear should spin" etc., it is crystal clear, what he meant by the new outlook on khadi. He wanted to use it as an instrument of a peaceful social change, which will lead to the establishment of a society based on non-violence, i.e., a non-exploitative society. This is basic, and those khadi workers who

would like to continue as before, had better realise this as early as possible. Then, not only will they realise the inherent weakness of their own position but perhaps also feel inclined to examine and consider the alternative objective.

Evaluation Committee's View

When the Evaluation Committee reported on the progress of khadi work, and according to some critics, failed to give due credit to the Khadi and Village Industries Commission and khadi workers for the great progress made in the production and distribution of khadi, they had obviously in view more the future of khadi work than a judgment on present achievement. Their main criticism was that khadi work was limited only to certain traditional areas, and there, too, it was not integrated in the life of the rural community. They felt that khadi had a future only if it was so integrated. This judgment was upheld by the Pusa Declaration which desired that khadi work should take a new turn (*naya morh*) so that it could satisfy this basic condition. Hence the *gram eka* programme and the decision to transform present khadi work into intensely developed *gram ekas*.

I will not dilate on the difference of view about the objectives now. I take it that even

the waverers would see light if they are told that they cannot utilise Gandhi's name for the type of work they are doing. But even a sincere acceptance of the new objective will not be of much avail, unless there is a clear realization of how khadi work can be reoriented to achieve this new outlook. What is the new society and what are its new values? The new society is non-exploitative, and the new value is that all socially useful work must carry an equal or a near equal wage to enable its follower to live in society as others do. That is food production, cloth production, oil production, carpentry, smithy, etc., all trades necessary for sustaining the life of the community, being equally necessary, must be equally remunerated. This is the real meaning of the expression "production for use".

A community produces for its needs, and all who produce share the articles. From this proceed certain deductions. First, there must be a sense of community. For this to be generated it is necessary that the main assets of the society must be with the community. Hence Vinobaji was very clear in his address to the khadi workers at Nabadwip in West Bengal that khadi work had no future unless it was integrated with agriculture. Khadi is not spinning for wages or mere production and consumption of cloth locally. It is primarily production of cloth by the community for its own needs. Now so long as a man owns his land, he holds it even against the community. But once he donates it to the community, he holds it for the community. It is really not so material, whether there is any change in the extent of his holding before and after the donation and to what extent he has shared his land with others. Even if he has not done so, the fact that he holds the land now for the community does make for a total

change in his outlook. Formerly he was cultivating his land. Now he is cultivating the community's land. He is still cultivating it for himself, but, as Vinobaji often says, the donation of land to the community itself creates a community consciousness which has to be further developed. Hence his insistence that khadi work should be started on a priority basis in *gramdan* villages. But if it is functioning elsewhere it is not to be stopped. Only the workers should understand that it cannot stand by itself and has to become sooner or later *bhoodan*-based. In practice, therefore, khadi work must go hand in hand with propaganda for *bhoodan* and *gramdan* and vice versa.

Production for Local Consumption

A community's production of cloth for its own use is the only guarantee that it will continue to do so without being too meticulous about its cost of production, and only in such circumstances can it stand competition in an open market from mill-made cloth. No cultivator calculates the cost of his home-grown rice or wheat. Similarly, where a community decides to produce its own cloth, it will naturally utilise the most efficient means available to it, but, beyond this, it will not bother to enquire into the cost of production of its cloth and the market price of cloth. As the late J. C. Kumarappa used to say, when we want to eat *hulwa*, we prepare and eat it, we do not calculate its cost to us and compare it with the market price at which it can be had. Similarly with cloth produced by the community. Here, again, the decision by the community is important. For it is only in circumstances in which the community decides to clothe and feed itself that such a method will be of avail. Such a decision by the community can only be translated into practice by fol-

lowing the principle of division of labour. Some in the community will produce food. Others will produce cloth. Still some will produce pots, and so on. But since the potter will need food and cloth and the cultivator pots and cloth and the weaver food and pots, and so on the produce of all will have to be shared by each. This may be done physically in terms of goods, or monetarily, by fixing wages, and, to prevent idleness or indolence, relating the wages to output. But it must be clear that within the community, the market will be for the goods produced by the community.

Utopian

This will mean such an enlargement of the family life of an individual as to encompass the whole village community in it. Is this ever possible? And if so, what would be the difference between this and a collective? It is rather difficult to answer the first question categorically—one can only point to the examples of some villages where this is the case after *gramdan*. In these villages it was even noticed that members of the village community, who got employment outside the village, accepted a salary decided upon by the community and remitted the balance to the community. All this may sound utopian. In one sense it is so. In Israel, about 300 such settlements are developing a progressively improving economic life, and they have been in existence for the last 40 years. This is not to deny the idealism behind the conception, but to indicate that it has also been practised elsewhere. From the standpoint of idealism all changes—especially revolutionary changes in social and economic structure—always appear to be idealistic particularly to those whose minds are not ready to grasp the new change

contemplated. In this sense *bhoodan*, *gramdan*, and even such innovations as the programme of cooperative farming would appear idealistic. The objective should not, therefore, be ruled out of hand on this account.

Freedom of Choice

But there would clearly be a difference between such a community and a collective. The similarity would be that in both the individual accepts social regulation, particularly of his economic life. But apart from its voluntary acceptance by the individual, the community would be free to plan its economic life as it chooses, unlike a collective, which is regulated in the interests of the large community known as the state. Of course this does not mean that the interests and actions of the community would always run counter to those of the state. But the community would be free to plan its production and consumption being guided by free market considerations.

The view is advanced by some khadi workers that the introduction of the ambar charkha has so revolutionised the khadi technique that it would now be possible to produce and market khadi on a very large scale. This view places more reliance on the larger production and sale of khadi rather than on its integration in the community's life. Even so, it has been greatly exaggerated, and faulty planning has resulted from the acceptance of this idea. Nothing is more distressing and demoralising for khadi work than to see huge stocks of ambar charkhas lying everywhere in production centres*. They are unlikely to be used in future, and will in all probability have

to be sold as junk. While ambar charkha could give more employment and reduce the price of khadi, the price-difference between ambar khadi and ordinary mill-cloth is yet so overwhelming that ambar cloth is not likely to be marketed beyond a certain maximum. Again, the idea that the introduction of ambar charkha has, to a large extent, solved the problem of giving employment through spinning has also its severe limitations. Spinning cannot be lifted from its position of a provider of residuary employment by the transition to ambar charkha, because it will still need state assistance for being marketed.

Not by Spinning Only

And while the responsibility of the state to provide employment to every able-bodied person is accepted, it will be an entirely different proposition to say that such employment must be given through spinning only. The state has various avenues of work, and can insist that spinning as a source of employment be made available only after other avenues are exhausted so far as all able-bodied persons are concerned. Therefore, the condition that all yarn produced on the ambar charkha must be purchased by the state at rates which will provide living wages to the spinner can only be accepted with the above qualification. The conclusion, therefore, is inevitable that khadi can remain a more or less permanent feature of the rural economy, if and only if, it is adopted by the

rural community as the instrument which provides its clothing, and therefore, integrates it with other economic activities of the community.

Objective of Khadi

A little thought will show that such integration involves the substitution of the present family economy by that of the community. Production and distribution must be planned by the community and not by the individual as at present. This is the change in the rural mind which has to be brought about before khadi can be made a permanent feature of the rural economy. Such production can stand on its own legs without any help from the state, while khadi, which seeks to provide employment only, depends for its existence on state assistance and vogue set in by Mahatma Gandhi. It will last till these two factors operate.

Let khadi workers not be misled into a false sense of fulfilment by the temporary increase in production and sales, and the conversion of the khadi bhandars into khadi bhavans. This is no fulfilment of the genuine purpose of khadi work, which is, as indicated above, to create a new society with new values. This was the dream of Mahatma Gandhi, which remains unfulfilled. A few such areas where khadi is adopted by communities as a means of providing clothing and then gets integrated in rural life, will go a longer way in propagating the ideal of khadi than an artificially boosted production and sale of a few crores rupees worth of khadi, which has tended to create vested interests amongst khadi workers, and has blurred the genuine objective which should have been before them all the time.

Nagpur
18 July 1963

* During the last two years the Commission has taken steps to put as many idle charkhas into active operation as possible. Mention may be made, among others, of the scheme for renovating ambar charkhas to make them lighter and for conversion of existing 4-spindle models into 6-spindle sets, wherever there is possibility of spinners working longer hours on the charkha. Till 31 July 1963 the Commission had renovated 26,705 charkhas and converted 10,561 charkhas into 6-spindle model.—Editor

MISSION OF KHADI

JHAVERBHAI PATEL

Khadi in its present form has not been able to deal with the basic and vital problems of our economy. Vinobaji calls this relief khadi. Khadi activity should be so organised as to enable artisans to grow in knowledge, power and vitality. This can be achieved by reducing the severity of their struggle for existence. Our villages too will have to reorganise themselves into bigger and viable structural units of operation to enable the villagers to widen their mental horizon and development opportunities.

THE time has now come when the khadi proposition needs to be restated. In 1947 Gandhiji had said "The various constructive activities had so far been carried on in a sphere apart from the political. With the assumption of power by the Congress the ministers could have availed themselves of their (constructive workers') experience and enabled them to spread on a countrywide basis what they had so far been doing on an experimental basis." We have now had experience of working out the khadi programme for over a decade under two five-year plans and we should be in a position to review as to how far this programme has made progress in the direction of fulfilling the mission of khadi or whether it is moving in the right direction at all.

What is the central mission of khadi? What are the *shruti* (श्रुति) and the *smriti* (स्मृति) of khadi? Are the khadi programmes formulated and evaluated from time to time in terms of this mission?

Incomplete Concept

Gandhiji put in a terse aphorism the *shuti* of khadi—खादी कपड़ा नहीं, विचार है।

Khadi is not cloth,^{*} it is a value. Evidently, under the limitations of the situation obtaining in his time, he could not work out the full implications of his aphorism. He could take only the first step of evolving simple production techniques suitable for the prevailing situation* and some form of organisation also suitable for the prevailing situation. Gandhiji believed in one step being enough for him. But important though this first step was, it was not the last step, not even the intermediary step. These steps were to be taken through exploration and experimentation. But it appears as though we are trying to be too loyal to the first step and dare not embark on new experimentation. The main reason for this state of affairs is the fact that the whole concept of the value or values that khadi stands for remains to be worked out in terms of the social order which would uphold and nourish those values. The concept being incomplete, further steps become impossible and naturally the whole khadi programme is being worked out in terms of the first

* Gandhiji had announced a prize of Rs one lakh for an efficient charkha.

step. This halts the onward march of the khadi movement. The evolving of the concept therefore, becomes the fundamental necessity of the khadi movement.

गुण पश्यत मा जगम्

'The modern man is essentially a man betrayed—betrayed by the innumerable political, economic, religious and technological priests, each highly specialised, each entrenched in his limited field and refusing to see the whole beyond the part.'[§]

Movement of Workers

In the absence of a clear-cut picture of the social order envisaged through the khadi movement the policy and programme are naturally governed by the part perspective. Khadi workers become specialists in certain aspects and function like all other specialists. No wonder the khadi movement till today remains the movement of the khadi workers rather than the movement of the masses. It is conducted under high pressure and has yet to take roots in the soil. It has yet to catch the imagination of the masses, who feel that the programme is being worked more to satisfy the sentiments of the khadi workers than to solve the problems of the people. It is defined and governed by the part perspective. The masses are unable to see its full prospects. The part perspective plays a predominant role in the controversy regarding the techniques of production. Even the transition from the simple to the ambar charkha had to overcome opposition. In this controversy sometimes a part is emphasised to the detriment of the whole and sometimes the limitations of the situation are idealised.

Usually some economic and social values like village self-sufficiency and social justice

[§] René Fouere *Krishnamurthy The Man and His Teaching*

are associated with the khadi movement. Khadi workers are expected to become the medium to propagate these values through the khadi programme. Shri U. N. Dhebar, Chairman, Khadi and Village Industries Commission expects workers to foster moral values. Because of the powerful factor of the influence of Gandhiji's personality, having its impact on the masses through his programme, we have been accustomed to emphasise the importance of this personal element in propagating these values but under the present circumstances, particularly it would be wise to realise the limitations of this influence. In regard to the position of workers, Shri Dhruva Prasad Sahu, Member, Khadi and Village Industries Commission, observes "In the past, there used to prevail an atmosphere of brotherhood and comradeship among khadi workers of an institution, but now with the increase in their numbers, the old ties are vanishing and these are being replaced by ideas of managerial control which involves change in relationship. The idea behind the khadi movement was to form a family of spinners, weavers and all other artisans. This idea has no place now in the management of the khadi institutions and the artisans are being treated as wage-earners." The stage has been reached when the khadi workers have formed their unions to regulate their relationship with their institutions. The relationship between the artisans and the institutions is practically commercial. In the circumstances, to expect either the khadi institutions or their workers to become the medium for propagating moral values through khadi would be wishful thinking.

Character of Programme

A more reliable medium than the personal influence of the workers is the charac-

ter of the khadi programme. Even the workers derive their inspiration from the programme. What is more, workers are drawn to a programme according to its character. If it is an inspiring programme it not only draws and inspires creative and talented workers but has its own intrinsic impact on the masses. Has the present khadi programme any such appeal? In the eyes of the people, it seems to have been stabilised in its present form. It seems to work within the limitations of the present social structure. Spinning which provides employment to the greatest number in khadi production, is offered as a spare-time occupation to the farmers and others and even that only as a residual occupation. It has not yet been developed as a whole-time occupation so as to draw a considerable number of workers away from agriculture. Khadi, therefore, does not help the reorganisation of agriculture into cooperative farming, which renders manpower surplus. Beyond providing relief, khadi has so far not been effective in decentralising economic power. It has hardly had any impact on reducing the disparities and gaps between the village and the town. Neither has khadi occupation made any contribution to the relief of the educated unemployed. The present form of khadi thus does not deal with the basic and vital problems of our economy.

Changing Formulae

Khadi workers have from time to time felt and expressed uneasiness about the programme. Some have expressed doubt as to the wisdom of working the khadi programme as a part of the Government five year plans. But it is not the agency of Government which has changed the character

or the traditions of the programme. The first five year plan for khadi presented by Shri Krishnadas Jaju to the Planning Commission was a programme of nothing more than an expansion of production of khadi cloth with the aid of subsidy. Vinobaji calls this अकाली (relief) khadi. Heart-searching among khadi workers gave the famous formula of *naya morh* evolved and adopted at a conference held in Chalisgaon in Maharashtra in 1958. Although this new formula conceived khadi as part of a plan for an integrated development of rural economy, partly owing to the limitations imposed by the Khadi and Village Industries Commission Act and partly owing to the hesitation of the khadi workers to adopt higher or what is now called intermediate technology which would really integrate khadi with the rest of the expanding economy, the khadi programme continues to be worked in isolation. The latest formula which now holds the field, is the substitution of sales subsidy by weaving subsidy. While this may have some salutary effect on achieving expansion of khadi production, it would hardly change the character of the programme in terms of transforming the social order.

Mission

What value or values did Gandhiji associate with the khadi movement? In his discussions with Shri Jawaharlal Nehru in 1946, Gandhiji put down "the highest intellectual, economic, political and moral development of man" as the objective or the mission of the khadi movement. "In this", he said, "there should be an equal right and opportunity for all". Through this movement he aimed at establishing the *survodaya samaj*, a classless society which

would help in the balanced growth of man in body, mind and soul

progress. He is satisfied with a modicum of labour and the reward for his labour

Equality of Opportunity

What is the root of the classes in our society? The root can be traced to the distinctions made between the nature of functions of the four *varnas* in the *Gita*. The *Gita** describes the work of the *Brahmin* and *Kshatriya* not in terms of external functions, defined as learning, priest work and letters, or Government, war and politics respectively, but entirely in terms of internal character. The work of the *Varshya* and the *Sudra* is expressed in terms of external functions and this difference has a deep significance. The first two take to external activities as a field and means for developing inner values. The last two are usually turned outward and are more occupied with the external values of their work than its value for character. Once this distinction in the growth of personality is allowed through distinctions in activities, it can never be obliterated through the best of the political systems. Real equality is the equality of opportunity for the development of personality. While the *Brahmin* and the *Kshatriya* get this opportunity, the *Sudra* particularly does physical toil under compulsion. Rude toil is enforced on his animal indolence by the needs of the body, by the impulsion of life and by some form of direct or indirect compulsion which society lays upon him. He performs toil for the society but makes no contribution to its

Viewed thus, are not the present khadi artisans working as *Sudras* merely for external values? This is the real challenge to the khadi movement. Can it make them turn inward? It should for their highest development. This is the real mission of khadi स्त्रियो वैश्यान्तथा शूद्रा Who are usually engaged in rude toil under compulsion and are working for external values, therefore, remain undeveloped, they should find in the khadi movement a transformation of their activities, which will enable them to work for inner values.

Shri Aurobindo observes that there are no exclusively different souls, one soul of knowledge, another soul of power, a third soul of vitality and a fourth soul of service, as if the fourth soul has to pass in successive lives through the third and the second stages to the first stage. Each soul in fact has all these four aspects of knowledge, power, vitality and service, with a predominance of one or the other aspect. There is a deep relationship between these inner aspects and the outer activities of man. Rightly done, the work of the *Sudra* develops knowledge, increases power, strengthens vitality and raises skill. This is the whole question. How should the activities be rightly done? It is the mission of the khadi movement to find out a solution to this problem. This solution should make for the highest development of the personality, as also for a classless society which would provide congenial atmosphere for such development.

How should the khadi activity be organised to enable the khadi artisans to grow in knowledge, power and vitality? Is khadi

शमो दमस्तप शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च
ज्ञानं विज्ञानं मास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् ॥
शौर्यं तेजोवृत्तिर्दाक्ष्यं युद्धचाप्यपलायनम्
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रकर्मस्वभावजम् ॥
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यवैश्यकर्मस्वभावजम्
परिचर्यात्मककर्मशूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥

in its mere physical aspect capable of doing this? The condition of the khadi artisans of long standing does not bear this out. More important than the physical thing is the setting—scientific and technical, social and philosophical—in which the activities are carried on. It depends on the setting whether the worker turns inward or becomes external minded, whether he works for internal values or for external values. What is this setting which can enable the worker to turn inward and to work for internal values? It can be briefly stated as one in which, there is (1) no struggle for existence, (2) no class struggle, and (3) simple living and high thinking. The first condition refers to the development of science and technology, the second to the right type of social organisation and the third to the proper philosophy of life.

Science and Technology

No anti-vital civilization can survive, says Shri Aurobindo and adds, "Matter and life are the actual basis of man. All the intellectual reasoning in the world, all the ethical idealism and spiritualism of which the higher faculties of man are capable, cannot abolish the reality and claim of our vital and material base or prevent the race from following under the imperative compulsion of Nature, its aims and the satisfaction of its necessities or from making its important problems a great and legitimate part of human destiny and human interest and endeavour."

It is in this endeavour that man has continually striven to develop science and technology, so as to reduce the severity of the struggle for existence. This is the fundamental issue. To the extent that this is achieved, man becomes free to pursue the deve-

lopment of his higher personality. But, otherwise, all his capacities and virtues are constantly exhausted* in surviving through the struggle. It is, from this point of view, that production and productivity are important values. Viewed in part perspective, hand-work has a certain limited virtue, but the overriding consideration from the whole perspective of personality development is the reduction of the severity of the struggle through higher production with the aid of science and technology. Vinobaji suggests that it should not become necessary for man to engage himself for more than five hours a day in productive work for maintaining himself and his dependants. And this maintenance should include not only the prime necessities but also the requirements of the higher life. Productivity should be achieved so as to provide for such a maintenance, as also savings which are essential for the progress of society. Freed thus from anxiety for maintenance, man can turn inward.

Overemphasis on hand-work often confuses the ideal with the practical problem of unemployment. If there is clarity first about the ideal, the practical question can be rationally worked out, taking into consideration factors such as the expanding economy through development of all its potentials and rising consumption and services in tune with the growing personality of our people. For this an approach of flexibility and experimentation is required.

The consensus of opinion which seems to have crystallised now after many years of discussions and heart-searching among khadi workers is to mechanise discriminate-

* ससारर्णव लब्धनक्षमनृधिया वृत्ति कृता सा कृणाम् यामन्वेषयता प्रयान्ति रूतत सर्व समाप्ति गुणा ॥

ly certain processes of khadi and village industries, particularly those which constitute the bottlenecks in production. It will be a revelation even to most khadi workers to know that on the same loom, weaving khadi out of ambar yarn is said to cost 35 naye paise more per yard than weaving cloth with mill yarn. This is due to the poor quality of ambar yarn owing to the defective, manually operated carding process. Carding is thus the main bottleneck in the khadi industry which deserves to be mechanised. If the aim is village self-sufficiency in cloth, removal of this bottleneck becomes of paramount importance and urgency.

An intelligent following of an occupation is an important condition which enables the worker to turn inward and to do the job for inner values. Today, all our productive occupations including khadi, agriculture and animal husbandry have become routine activities, not yielding inner values but pursued merely for external values. Because the driving force of the inner urge and scientific knowledge is wanting, even the outer values suffer. Swami Vivekananda ascribes our downtrodden condition to the तमस् inertia and ignorance of our masses. The greatest lesson of the Israel Village Settlements is that only the developed personality of the workers can develop the economy.

All farmers in Israel received scientific training before they took to agriculture as an occupation—in their case it was a necessity because none of them was a farmer by tradition. The extension services in Israel not only advise farmers about the use of the best seeds, fertilisers, implements and insecticides, but also conduct courses to provide scientific knowledge to farmers in

all branches of agriculture, also, for subjects of general interest in life like nutrition, cooperation and philosophy in which women participate equally with men. I found a wide mental horizon of both men and women in these village settlements. While men engage themselves in productive activities, cooperatively or as self-employed persons, women are not confined to mere household duties, they take charge of all village services like mutual aid, co-operative shop, education games and playgrounds, etc. on a voluntary basis. Israel being a very small country, its villages are not geographically isolated. But what is of interest to us is the fact that by their way of life they do not suffer from cultural isolation either.

The success of the khadi movement will really be judged by the success we achieve in breaking the geographical and cultural isolation of our villages. Thus intermediate technology and *nai talim*—intelligent and scientific following of occupations and activities—are two great factors to make नियो वैश्यास्तथा शूद्रा turn inward and work for inner values.

Social Frame

The ideal society in which man can turn inward is one which is an extension of the family. Man should be able to turn to society in a spirit of सच्च शरणं गच्छामि for widening of outlook and higher inspiration. To make man free from anxiety this society provides social security in respect of employment, education and health, and thus creates conditions in which man can turn inward. Since competitive economy makes man turn outward, this society adopts co-operative economy, allowing full scope for self-employment. But trade which pools the

fruits of the labour of many is strictly allocated to the cooperative sector. In place of centralised mass production, such a society organises, in the words of Gandhiji, decentralised production by the masses. If both systems take full advantage of science and technology, production would be greater in the latter system, because, while the centralised system restricts production to the most efficient units, putting all other units out of action, the decentralised system makes the fullest use of every available resource, each* one of which adds to the total. Such a society would really be a welfare society providing sufficiency of income from self-employment and abundance of social services from public wealth.

Reorganisation of Villages

In the present form our villages can hardly hope to aspire for the life envisaged above. Dispersed as they are, they can hardly hope for modern amenities and services. For widening their mental horizon and development opportunities, they will have to reorganize themselves into bigger viable structural units of operation. They have got such units in the political sphere in the form of the zila parishads. In the economic sphere, they will have to evolve suitable cooperative units which would eliminate competition and allow full and rational use of local resources, both natural and manpower, to the equal advantage of all the members. In such a cooperative structure, the bigger units in industry will serve either as feeder centres or as service centres for smaller units of production and will not be

interested in suppressing them. For this purpose, scattered villages will have to be linked through the creation of service stations each serving a group of villages, a device which can break their geographical isolation.

Simple Living, High Thinking

Developed science and technology and a good social frame may provide creature comforts and social justice to man but need not by themselves lead him to the pursuit of higher objectives in life. For this he must also possess a proper philosophy of life and aspire for a balanced** growth of his personality. How powerful an influence philosophy has on life is borne out by observing the working of different types of societies.

In the primitive societies of Africa most of the attributes of a classless society are discernible. Practically all productive work is carried on by hand. Agriculture is not done by animal power, nor by manpower but by womanpower. It is ऋषि खेती carried to its extreme. All the land is communally owned and every family has a right to cultivate and get maintenance from it. Till recently, currency did not enter into the local exchange of goods and services which were carried on on barter system and each tribe was self-sufficient in regard to its prime necessities and defence. Life was spent in struggle against nature, struggle against disease and wars with different tribes. This represents the model of प्राकृत समाज in which there is simple living and simple thinking.

There is the model of विकृत समाज found in the exploiting countries. Here science and technology have reduced the

*अमत्र अक्षारनास्ति
नास्ति मूलमनौषधम्
अयोग्य पुरुष नास्ति
योजकस्तत्र दुर्लभ ॥

† धर्मार्थं कामा सममेव सेव्या ।
य एकसेवी स नरो जघन्य ॥

struggle for existence but because of the ideal of high living the struggle for existence has been replaced by class struggle. This is the type of society in which there is high living and simple thinking (in terms of the ideal)

Thus, simple living, in the sense of simply living, or science and technology alone are not enough or capable of guiding man in the pursuit of higher life. *संस्कृत समाज - sarvodaya samaj* emphasizing and inculcating moral and spiritual values enables man to rise higher. *Sarvodaya samaj* gets over both the limitations of the *प्राचिन समाज* and the weakness of the *विकृत समाज* and enables man to lead full and balanced life in body, mind and soul. It is a model in

which there is simple living and high thinking

It is the mission of the khadi movement to establish such a *sarvodaya samaj* through the creation of models in selected areas. But khadi, as an isolated item of programme, cannot accomplish the task even with the best of sentiments. This is possible only when khadi as representing the values of *sarvodaya samaj* becomes typical of all the activities of our society. It is through this realisation that Gandhiji evolved the *samagra* or integrated programme in 1944. *Sarvodaya samaj* demands integration not only of economy but of the whole life of man.

New Delhi
16 August 1963

We must give up all external fears. But the internal foes we must always fear. We are rightly afraid of animal passion, anger, and the like. Internal fears cease of their own accord, when once we have conquered these traitors within the camp. All such fears revolve round the body as the centre, and will, therefore, disappear as soon as one gets rid of attachment for the body. We thus find that all external fear is the baseless fabric of our own vision. Fear has no place in our hearts, when we have shaken off the attachment for wealth, for family and for the body. Nothing whatever in the world is ours. Even we ourselves are His. When we cease to be masters, and reduce ourselves to the rank of servants, humbler than the very dust under our feet, all fears will roll away like mist, we shall attain ineffable peace, and see Satyanarayana (the God of Truth) face to face.

Mahatma Gandhi

POTENTIALITIES OF AMBAR CHARKHA

SHANKARLAL BANKER

*If spinners get opportunities to see for themselves how charkha can be plied efficiently it will enthuse them to improve their performance
Experimental and demonstration centres can go a long way towards fulfilling this objective*

INDIA is predominantly a land of villages with the majority of rural population poor and unemployed or underemployed. It was with a view to providing employment to these villagers and enriching their lives that Gandhiji launched a programme for the development of khadi industry and established the All India Spinners Association and the All India Village Industries Association. The Indian National Congress also took up this programme. The National Government formed after the attainment of independence established the All India Khadi and Village Industries Board (now Khadi and Village Industries Commission) for efficient implementation of the programme. As a result of these efforts khadi work has spread to nearly a lakh of villages and more than 15 lakh persons have been provided with gainful employment in the khadi industry.

Improvements in Traditional Charkha

When Gandhiji initiated his programme for the development of handspinning, traditional charkhas were being plied in different parts of the country. Though this traditional model was popularised in the be-

ginning, Gandhiji felt the need for effecting modifications and improvements in it for making its popularisation on a wide scale possible. The charkha underwent many improvements as Gandhiji himself devoted considerable attention to this work. The yervada charkha (box charkha) was evolved as a result of efforts in this direction and soon tens of thousands of these charkhas became popular with the people. These box charkhas were also used in schools to train boys and girls in spinning.

Besides being cheap, the box charkha was light and portable. It was smooth in operation, occupied less space and above all its productivity was higher than that of the traditional model. Owing to these merits the box charkha gained in popularity day by day.

However, not resting content with the evolution of the box charkha, Gandhiji desired the evolution of a charkha with a productivity of 16,000 yards of yarn of good tensile strength and evenness in eight hours. He, therefore, announced a prize of one lakh of rupees for an efficient charkha. A number of specimens were submitted, but none satis-

fied the conditions laid down by Gandhiji. The award was hence withdrawn. The question of effecting modifications in charkha to make it faultless and more efficient, however, continued to claim Gandhiji's attention. He also directed his efforts towards raising the efficiency of the spinner, popularising the use of good slivers and increasing the production of yarn with good tensile strength.

Ambar Charkha

Later came the ambar charkha which was evolved by Shri I. Kambarnath of Tamilnad. This model fulfilled some of the conditions laid down by Gandhiji. The khadi workers welcomed the new model, but the research workers felt that there was considerable scope for making improvements in it. Consequently, the Akhil Bharat Sarva Seva Sangh constituted the Ambar Prayog Samiti which took up the work of making improvements in the ambar charkha. As a result of its continued efforts a model with a productivity of 16 hanks of yarn in a period of eight hours was evolved.

It is natural that more attention has been paid to the development and popularisation of the ambar charkha which has a higher productivity, with its four to six spindles, than the box charkha which gives a production of three hanks of yarn in a period of eight hours. The processes of the two charkhas are quite different. The box charkha operates according to the 'mule process,' while in the ambar charkha the 'ring process' is followed, in which the winding of yarn on the spindles is done simultaneously with spinning, and, consequently, the output is higher than on the box charkha because in the 'mule process' spinning and winding have to be done

separately. Even in the mills the 'ring process' is followed.

Instrument for Carding

The processes of carding cotton and preparation of slivers are also of vital importance in handspinning. In the past carding was done on traditional instruments which were not efficient. Later on the hand-operated *madhyam dhunki* came into use. This was followed by the *dhunai yantra* which was evolved as a result of researches and experiments. But as the carding done on this instrument was not satisfactory, the Prayog Samiti took up further research on this instrument. The carding instrument which was devised by the Samiti, has facilitated the operation of separating the fibres and removing dust without causing damage to the fibres. There are two models of this instrument—hand-operated and pedal-driven. On the former, one can card 15 *tolas* of cotton and on the latter 30 *tolas* of cotton in an hour. Experiments have also revealed the possibility of preparing slivers (*tapes*) for ambar spinning on this instrument.

Though costlier and more complicated in its operation than the box charkha the ambar charkha is an efficient instrument giving greater production of better quality yarn. An efficient device capable of giving good output in the decentralised sector of the textile industry is necessary in this age of technological advancement. This, in fact, was what Gandhiji desired and strove to achieve. It is, therefore, that the ambar charkha which has a higher productivity and is capable of providing better wages to the spinners—who can also spin on it with ease—and which facilitates production of better quality

khadi, should be popularised on a large scale

Guiding Points

Still some points should be borne in mind with regard to its use and popularisation in the field They are

(1) The ambar charkhas provided to the spinners should be free from any defects Adequate arrangements should also be made for their immediate repairs when necessary

(2) The spinners should be given thorough training in the operation of the ambar charkha They should also be made conversant with the calculations necessary for spinning yarn of different counts and different twists They should also be made familiar with all the parts of the ambar charkha and be trained to operate it with skill to avoid any breakdown and be able to repair it They should know how to protect the charkha against rust, in case it has to be kept idle for some period The spinner should know how to choose cotton suitable for producing yarn of particular counts Adequate arrangements should be made for the supply of these varieties of cotton

(3) Training in typewriting or in working on a sewing machine does not make one an expert Constant practice alone will impart skill to the worker Similarly, the spinners on ambar charkha have to practise regularly to acquire good speed and efficiency to be able to produce quality yarn of good tensile strength Even a spinner on the box charkha needs continuous practice

Experimental and Model Centres

As handspinning is of vital importance for the economic regeneration of the villagers, it is necessary to create an atmosphere

conducive to the cultivation of the habit of spinning among the people and to induce them to develop faith in the programme and to acquire skill in the efficient use of the instruments It is equally necessary that the yarn spun by the spinners in their homes after the conclusion of their training period should be of a good quality This can be achieved if the spinners get an opportunity to witness spinning being carried on efficiently in homes by other spinners in the centres and villages around them With this end in view it is necessary to establish experimental and model yarn production centres so that the people in the surrounding areas could realize the potentialities of ambar charkha If khadi work is developed in every household on an efficient basis on scientific lines it would go a long way in expanding khadi work It will help in accelerating the speed of khadi work if spinners and workers could visit centres where work is well established and study carefully the work carried on there

There should be provision for demonstrating improved models and improved techniques in khadi centres on the lines of model farms and agricultural research centres established to promote the cultivation of better varieties of farm products The farmers who show good performance are given awards as an incentive Similar steps are taken for the development of animal husbandry The villagers are given opportunities to get intimate knowledge of these developments, which inspires them to adopt better techniques and processes Facilities of this nature should be provided in khadi industry

Prayog Samiti Centre

It would be desirable to man all such centres with the workers of the Ambar

Prayog Samiti who have deeper knowledge of the capacity and efficient operation of the charkha. The Prayog Samiti should organise and conduct these experimental and model centres in selected places in States where spinning is carried on on a large scale. One such centre is being run at Sri Amargarh under the aegis of the Prayog Samiti. The experience gained at the centre shows that if similar centres are run in every State to develop spinning and weaving on scientific lines, it would inspire the spinners and the workers to increase their efficiency. Similar centres are also being conducted by the Khadi and Village Industries Commission. It is desirable that the institutions themselves should run such centres. Therefore a programme should be chalked out to further expand the existing centres and to organise new ones in those areas where there are none. If particular attention is paid to this work and good care is taken for ensuring proper development of these centres it would lay a strong foundation for the khadi programme.

A large number of people in the countryside would take to ambar spinning if a network of experimental and model centres in which spinning and weaving work is carried on on scientific lines is established, a band of spinners and weavers is trained in performing the processes of spinning and weaving efficiently and facilities are provided to the artisans of other regions to visit those centres and study the work being done there.

Jail Incident

This reminds me of a talk I had with Gandhiji in Yervada Jail in 1922. Then Gandhiji used to spin four hours daily at the rate of 250 yards of yarn per hour. He felt that this rate of production was too

low, and hence tried to spin faster. He had seen Shri Keshav Gandhi, son of Sri Maganlal Gandhi, spinning yarn at the rate of more than 450 yards an hour at the Satyagraha Ashram which had induced Gandhiji to strive to catch up with him. The point is that the spinners' enthusiasm for increasing their skill and efficiency can be stimulated if they get an opportunity to watch a group of skilled spinners working efficiently in a centre.

Learning through Observation

Another incident is of Sabarmati Jail. In spite of their efforts for a period of six months to improve their production, the inmates of the Jail could not spin more than two hanks of yarn per hour, although they had efficient instructors to train them. When they were given an opportunity to witness spinning performed by the instructors and the workers of the Prayog Samiti, on the first day itself they felt confident that they too could attain the same speed in production as the workers of the Samiti. On the second day again a spinning demonstration was arranged for the benefit of the prisoners which lasted for about four hours. Consequently, all the prisoners developed full confidence in their capacity to spin. As a result of the impact of this demonstration the jail inmates succeeded in increasing their rate of production from two hanks to five hanks of yarn in a day.

Let me cite yet another example. It refers to an incident which occurred in 1959-60 during the annual session of the Indian National Congress at Nagpur. The workers of the Prayog Samiti who carried with them the three-spindle composite drum charkha, claimed that they could spin eight hanks of yarn in four hours. But Shri Shamrao

Muley from Waidha, who was known to be an expert spinner in the country, doubted this claim. In order to prove the claim, one of the workers of the Prayog Samiti, Shri Ramayadibhai, accepted the challenge of spinning eight hanks of yarn in a period of four hours. He was able to produce $8\frac{1}{2}$ hanks of yarn in four hours. Seeing the demonstration, Shri Shamrao and his friends declared that they could easily better Shri Ramayadibhai's performance.

Actual observation of demonstration of spinning thus serves to stimulate spectator's interest and increase his faith in the potentialities of spinning. These examples prove that the establishment of experimental and model centres, particularly, in those areas where khadi work has made fairly good progress, is necessary.

Both the ambar and the box charkhas are useful spinning implements, both have

their own place in the sphere of spinning. The box charkha is more suitable for affording relief to the people affected by drought, floods and other natural calamities and for those who are physically handicapped. Ambar charkha is generally meant for able-bodied, intelligent and skilled artisans who wish to increase their earnings.

For the purpose of providing gainful employment to the people through handspinning in the rural areas, ambar charkha can prove to be an efficient and useful implement. Hence the urgent need of the hour is to propagate vigorously its use in the villages. This is possible only when experimental and model ambar spinning and weaving centres are established and the villagers are provided opportunities to learn through first-hand experience by visiting such centres.

Ahmedabad
26 July 1963

There are three qualifications required in those who have to fill the highest offices—(1) first of all, loyalty to the established constitution, (2) the greatest administrative capacity, (3) virtue and justice of the kind proper to each form of government, for, if what is just is not the same in all governments, the quality of justice must also differ.

Aristotle *Politics*

A PLEA FOR REALISM

J D SUNDRAM

Gandhiji wished to usher in a non-exploitative social order that assured economic independence without major social or economic dislocation. The Khadi and Village Industries Commission which took over the activities of the All India Khadi and Village Industries Board, has been trying, through its programmes of building from below and naya morh, to attain this goal envisaged by Gandhiji. While reviewing the achievements of the Commission in this direction, the writer who was secretary of the Khadi and Village Industries Evaluation Committee (1960), is critical about several aspects of the policy and programme. Though, obviously, we do not agree with the criticism levelled by Dr Sundram we publish the article in the belief that free and frank appraisal is an essential prerequisite for stimulating development. We would hence welcome comments on the points raised in the article—Editor

GANDHIJI'S advocacy of khadi and village industries was based on his recognition of the urgent need to assist (i) the poorest among the poor by giving them a means of supplementing their meagre incomes as a first step in a programme for their social and economic uplift, (ii) the villages from being impoverished of their wealth, output and personnel by the fast growing urban areas, and (iii) the preservation of basic moral and social values in the traditional Indian way of life, particularly that part of it that inculcated, in one way or another, to a smaller or larger degree, basic social virtues of mutual aid, co-operation and interdependence. The political conditions that prevailed during his time invested his programme with national (political) and cultural (social) significance.

Gandhiji's programme for the revival and development of khadi and village in-

dustries was generally dismissed as one that "put the clock back" when the critic was charitable, and as that of "a visionary and a crank" when the critic chose to lay claim to "modernity". A large number of his close associates, however, saw in his programme a revolutionary weapon of great potential for the restoration of all that was good in the Indian way of life. But Gandhiji was not concerned with either the criticism or the commendation of his programme, his main concern originated and continued to be in the evolution of a programme of organised effort that would activate the masses, particularly in the rural areas, into purposive, productive endeavour to realize in practice the three-fold objective mentioned above. It was on this account that Gandhiji's interest ranged from the preservation and development of the existing skills of handloom weavers, who were the first to attract his attention, to the

development of a decentralized spinning industry to assure them regular and adequate supply of yarn. The same concern explains his sustained interest in and advocacy of technical research, of training, and the pursuit of higher productivity and earnings of artisans. All efforts at improvements, though welcome in themselves, had, in his view, to subserve the overall social objective, viz., preservation of what he considered to be the basic social values of the Indian way of life. In brief, his was a socio-economic programme that had as its objective the establishment of a non-exploitative social order that assured economic independence, without major social or economic dislocation. His programme as a result was constantly changing, growing and improving in content, evolving into as efficacious an endeavour as he could make it.

Decade of Preparation

During the decade, 1953-1963, the development of khadi and village industries has come to be accepted as an integral part of the planned, national effort at socio-economic development. This acceptance, though originally capable of being dubbed as political, became by the end of the First Plan period, truly national. Starting almost in a vacuum, the Khadi and Village Industries Commission has carried on the work, initiated by the All India Khadi and Village Industries Board in 1953-54, of setting up statutory bodies in the States, capable and willing to take over from it the responsibility for implementing statewide programmes of development. The gradual evolution of the essential framework—administrative and organisational—to translate policies into effective programmes of economic amelioration and of economic up-

lift marks the end of the much needed period of preparation for large-scale effort. Time is, therefore, appropriate to consider whether the present policy and approach to the development of these industries are appropriate and likely to facilitate the realization of the objectives of Gandhiji.

Basic Policy

In its policy statement *Building from Below*, the former All-India Khadi and Village Industries Board advocated the adoption of improved tools and implements that held out the promise of higher productivity and incomes to artisans.¹ Organisationally, it considered the cooperative as the most effective structure to facilitate the progress towards the establishment of a non-exploitative society.² Cooperatives of self-employed artisans were, therefore, to be assisted to produce progressively improved qualities of goods, market them mostly in the areas of their manufacture, eliminating the incidence of transport and other similar avoidable costs, and, over a period of time attain the status of self-supporting units.

Integrated development, or what has come to be known as *naya morh*, adopted as the basis of the programme during the Third Plan period, is essentially the same programme, so far as the development of khadi and village industries is concerned.³ Organisationally, however, the emphasis was shifted, at least in the initial stages, to any local body of enlightened leaders, though multi-purpose cooperative societies

1 *Building from Below*, All India Khadi and Village Industries Board, 1956, chapters V and VIII.

2 *Ibid*.

3 *Third Five Year Plan for Khadi, Khadi and Village Industries Commission*, 1961.

continue to be the final pattern of organization. Its emphasis, as of the earlier *Building from Below*, is on the adoption of improved implements and tools, higher productivity, lower costs and prices, and higher incomes.⁴

Policy and Practice

As statements of broad policy, neither *Building from Below* nor *naya morh* is in conflict with the basic social objectives that Gandhiji desired the development programmes for these industries to pursue. The steadily widening gulf between profession and practice, however, is seen only when the actual programmes, their structure and their dynamics are studied in relation to those objectives. The programmes *per se* may not be found objectionable, as they, after all, represent no more than a set of measures for assisted effort, but the measures of continuing importance, adopted by the Commission itself or efforts assisted and encouraged by the Commission fall into another class altogether. The progress made by khadi and each of the village industries in its charge during the decade, 1953-63, measured by the volume of financial disbursements and utilization, production and sale, number of new institutions registered or recognized by the Commission, may, as compared with the conditions prevailing prior to 1953 or any other given years be considered to be impressive and commensurate with the actual outlay, even though official financial audit of progress may question such a claim. The real or true measure of progress is not the rate of increase in production and sale, but the nature of the socio-economic change either actually brought about or prepared for. It is from

this point of view that the following comments are made and suggestions offered for consideration.

Objective Assessment

The justification of khadi and village industries in the Indian economy is their capacity to provide employment to the needy on a large scale with little or no additional capital cost. The multi-tiered programme of training necessitated by the introduction of the ambar charkha programme was justified by the promise of a considerably enhanced output per unit of effort, improved quality of yarn, reduction in costs and, therefore, in the rates of rebates and subsidies.⁵ The ambar charkha programme, it was claimed, was capable of easing the pressure on the land by drawing to it able-bodied persons in full-time employment.⁶

A critical scrutiny of the progress of khadi, and the role of the ambar charkha programme in it lends no support to these claims. The poorer and weaker sections of the population in the rural areas have generally ignored the entire industry as it promised them nothing of any continuing economic significance.⁷ Those employed in handspinning on the traditional or ambar charkha, work only part-time, the full-time workers being numerically, or from any other point of view, of little significance.⁸ What is, however, of greater importance is that, except those of the insignificant number referred to above, the earnings of hand-

⁵ *The Ambar Charkha Programme, Its Economics*, All India Khadi and Village Industries Board, 1956.

⁶ *Khadi and Village Industries, Second Five Year Plan*, All India Khadi and Village Industries Board, 1956.

⁷ *Report of the Khadi Evaluation Committee*, chapter 8.

⁸ *Ibid*.

⁴ *Ibid*.

spinners on the traditional and ambar charkha are meagre, and their contribution to the basic objective of economic uplift, as distinguished from economic relief, is, therefore, negligible.⁹ The almost total failure of khadi to attract and retain male spinners, in view of the prevailing social and other inhibitions, should be attributed to the basic inappropriateness of the programme as a source of employment of any economic importance.¹⁰

From the point of view of assuring a regular and adequate supply of yarn to handloom weavers as well, the khadi programme has been a failure. Whatever the cause, handspun yarn continues to be a drag on the productivity of handloom weavers, and their earnings, and the cost of weaving has generally continued to be high, in spite of an appreciable deterioration in the quality of cloth. Many inducements have had to be offered to handloom weavers of mill yarn to undertake weaving cloth from handspun yarn, in addition to providing them initial training in the use of handspun yarn.¹¹ That a number of khadi weavers who are on the rolls of khadi institutions today openly switch over from time to time, to weaving cloth with mill yarn¹² testifies to the technical and economic failure of handspun yarn as a viable substitute for mill yarn.

The capital investment in the khadi programme, particularly the ambar charkha programme, has yielded no appreciable returns judged from any point of view. Calculated on the basis of the percentage of idle ambar charkhas to the total number distributed, the expense involved in the re-

novation and reconditioning of unserviceable or defective charkhas, the deterioration in the quality of cloth the yarn spun on it has brought about and, above all, the serious problems created as a result in the retail sales market and the consequent accumulation of stocks with institutions, the capital cost has not been inconsiderable.

The greatest defect of the khadi programme, as a whole, and the ambar charkha programme as it has been implemented in particular, is the staggering waste of time, energy and money spent on the training of personnel,¹³ for whom there is neither current nor future demand either in khadi or any other industry. If it had been possible to market an increasing volume of progressively improving varieties of cloth at steadily lower prices, there might have been a fairly large, albeit a closed, market for handspinners on the ambar charkha. Consumer resistance, brought about partly by deteriorating quality of cloth, partly by high prices and partly by steadily falling incomes, indicates that there is no real demand for handspinners on the ambar charkhas, and the expenditure incurred on training different categories of personnel has not yielded, and is not likely to yield, any returns socially or economically of any appreciable or lasting significance. Sooner or later, these "trained" personnel will have to turn to other jobs wherever they are available.

Alternate jobs such as road building, bunding, *bidi* making etc., in spite of their irregularity, and consequent lack of dependability, always draw away spinners, because, essentially, hand-spinning does not pay. In other words, handspinning on the traditional and/or ambar charkhas is not

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, also see *Handbook* for details of assistance

¹² *Report of the Khadi Evaluation Committee*, chapter 8

¹³ For details of the results of the Training Programme, cf. *Report of the Khadi Evaluation Committee*, chapters 8 and 10

a "salable" skill such as carpentry, blacksmithy, masonry, etc. Demand for this "skill" is restricted to a few institutions, the scale of whose operations depends on a host of considerations wholly irrelevant to the needs of the artisans

Decentralisation and Khadi

The critical assessment made above does not, however, question the need for decentralisation as such. Socio-economic evaluation of urbanization that has been a concomitant of industrialisation points to decentralisation of social and economic life as the only possible solution to save Man and his moral values. Decentralisation of economic organisation and activity, does not, however, preclude the adoption of the most advanced, modern techniques of production,¹⁴ as the experience of the U S A, the U K and Switzerland shows. Acquisition of the necessary skills though time-consuming, gives the artisan a range of choice and, therefore, mobility between a number of alternative trades. In other words, it gives him a marketable skill and, therefore, makes him an independent, useful and productive artisan that a handspinner is never likely to be. To learn carpentry or a similar trade, no doubt, takes longer than handspinning, but an industrious carpenter of average skill earns several times as much as the *most skilled* hand-spinner for an effort of equal duration. It is the choice, therefore, of skills, rather than merely scale of effort that thus becomes important.¹⁵

The elaborate, intricate training pro-

gramme, necessitated by the ambar charkhas, cannot, objectively, be said to have taught the large number who were covered by it a skill that is salable in the "open" market. Khadi, no doubt, requires handspinners, but it has no inherent strength to pay wages at acceptable rates. What it has at best achieved is to provide relief, and that, too, objectively speaking, on a marginal scale. From the larger national point of view, can a programme of mere relief of totally ephemeral importance claim or receive financial assistance of the magnitude that the ambar charkha programme requires? Teaching of a skill of practically no objective value can hardly claim to have either a national or a continuing importance to be integrated with national programmes.

Technical Research

Towards the evolution of better tools and implements, the Commission has authorized considerable expenditure by way of grants to individual institutions, has set up a research institute of its own and also assisted artisans recommended by institutions/agencies. Here also, an objective view of results achieved so far needs to be taken.

Since the first ambar charkha model was fabricated in the early fifties, the total expenditure on "research" incurred by the Akhil Bharat Sarva Seva Sangh and its affiliated institutions, the Khadi and Village Industries Commission has been substantial. To what end has this research been directed? There was absolutely no question of evolving any new "technique" as such, but the adaptation of already known and perfected techniques, to the requirements of a decentralized economic order. What has, however, taken place is an expenditure of valuable time, energy and money on experimentation to effect minor

14 For an illustrative account of how this can be reconciled with and compensation for the unskilled masses in India, cf. *Building from Below*, Part III.

15 For illustrative details of what salable skills can secure artisans from socially backward classes, cf. *AICC Economic Review*, Vol. XV, No. 317, July, 1963, p. 26, et seq.

improvements and to discover ways and means of reducing if not eliminating dependence on what are described as "centralized" industries. In relation to the "prescribed objectives" some of the implements devised at some of these centres may be considered as "operationally efficient", but the almost total preoccupation with devising an instrument that can be fabricated in the "villages" is open to question. This preoccupation cuts across the entire concept of an integrated economy, in which every sector depends and supports every other. It is an implicit condemnation of all large-scale industries which in independent India are as much "swadeshi" as "khadi" claims to be. The dominance of "orthodox" (no-changers of earlier times?) constructive workers has reduced technical research to a farce. In spite of nearly a decade, no instrument in any process of the industries in the charge of the Commission, incorporating advanced technique has been successfully evolved. The so-called "technical research" has failed to yield any implement, which is satisfactory from the point of view of technical and operational efficiency, productivity, cost per unit of output and, therefore, of prices. Implements devised so far in laboratories, though definitely superior to those currently in use, do not have significantly higher productivity, or represent successful adaptation of accepted techniques or lend themselves to standardization and large-scale manufacture. Specialized and, worse, personalized attention possible in laboratories cannot be given in the field when the artisans do not have and cannot acquire, except over a considerable period of time, the requisite skill, which, as pointed out above, does not offer any prospect of material benefit.

From what has been said above, it can

be inferred that though research of some kind has been, and is being carried on, there has been no real earnestness in those efforts for an effective adaptation of modern techniques, evolution of improved tools and implements with significantly higher productivity and, therefore, capable of attracting and retaining in the industry able-bodied men capable and willing to work full-time. Technical research has been, and continues to be, handicapped by orthodoxy that opposes any real change. This doctrinaire approach and attitude has disabled the Commission from acting on the recommendations of Committees, such as the Village and Small-Scale Industries (Second Five Year Plan) Committee, Evaluation Committees for Khadi and Village Industries and also of Power Committee. The result is that the acceptance of recommendations affecting basic policy and suggestions to make the programmes of real social and economic significance has amounted to be no more than lip service. In practice, programmes have remained the same in all essentials and been as ineffective as before the Committees examined and reported.

Purposeful Pragmatism

The doctrinaire approach of constructive workers has been responsible for the prevention of a break-through to a programme of real effectiveness. Constructive criticism offered in a spirit of understanding has as a consequence evoked spirited, and often, irrelevant defence that ignored the substance of the suggestions. In these circumstances, the programmes of development have failed to have any impact on the employment situation, and all the claims and arguments in their defence remain, when all is said and done, empty and ineffectual.

The fact of massive, growing unemploy-

ment and underemployment is no longer questioned but what has been and continues to be doubted is the effectiveness of khadi and village industries as instruments for the mitigation of its severity because of their total failure during a whole decade to attract on any appreciable scale anywhere the unemployed and the underemployed. The migration of labour from the bulk of these industries to any other alternative occupation reflects the general reluctance of labour to continue in the industry because of the inadequate levels of returns.

Basic Principles

The basic principles that animated Gandhiji in his advocacy of khadi are as true today as during his lifetime. Khadi, in addition to being a commodity produced by a certain technique, represents sensitivity to social ills. In the changed conditions of the world, with its own scale of values and preferences, khadi as a body of basic principles, has relevance as the values it bespeaks are of enduring value.¹⁶ In the economic and social spheres of human activity, khadi would represent a decentralized economic and social organisation, specially oriented to raise the standards of living of the population and reduce inequalities of opportunity for social, cultural and economic improvement.

The ideal of "self-sufficiency" which is basic to the khadi creed has become irrelevant in the conditions of today. Man was born a social animal, and in the society of his compeers alone can he find his fulfilment. Religion, social and cultural life as much as economic efficiency necessitate co-operative endeavour and pursuit of common

ideals. Division of labour, condemned by the self-sufficiency concept, underlies all activity. Political, economic and demographic trends today emphasise the need for global thinking and nuclear developments necessitate the relegation of even national frontiers to the background, as they have ceased to have any real meaning. In this context, to hark back to self-sufficiency or seek freedom from dependence on large-scale industries is to fly in the face of inescapable realities. It is this lack of realism that lies at the root of the intellectual inertia to go forward with determination.

Similarly, there are many inhibitions about the pattern of organization and employment. It is commonly held, as though it were axiomatic, that factory organisation or employment in any form is bad, and that cooperative organisation is *per se* superior. Individual initiative and enterprise cannot but result in one person getting ahead of another and employment in a cooperative can be worse than in a factory, if its management is in the hands of vested interests. Not all the khadi institutions are uniformly philanthropic any more than all factory owners or managers are cruel exploiters. Realism indicates the need to discard these ancient, time-worn prejudices.

In the context of modern, industrialized fast developing economies, social welfare is recognised to be the responsibility of the State, the employer and the employee, recent labour, factory and industrial legislation is based on the firm acceptance that social welfare involves tripartite planning, participation and administration, the State's role being essentially that of an arbitrator. It is, therefore, necessary for us to consider, in this context, all forms and patterns of organisation as equal intelligent partners in the socio-economic project of development.

¹⁶ For a fuller exposition of the concept of Khadi, cf. *Report of the Khadi Evaluation Committee*, chapter 2.

Pragmatic approach that recognises the possible beneficial role of private enterprise may facilitate faster development, because it will secure the active cooperation of the more enterprising and forward looking sections of the community. Moreover, the existing laws governing industry, labour and social relations in general are extensive, and, implemented effectively, they can, without major changes, protect the rights and secure the privileges of all the sections of the community. Social awareness of mutual obligations towards the solution of common problems for the realization of commonly accepted ideals is the *sine qua non* of all decentralized socio-economic development, and it is this objective that must be vigorously and continuously pursued and attained.

Realistic Reorganisation

Acceptance of the thesis advanced above is capable of removing the existing barriers to the evolution of a truly integrated approach to socio-economic development of rural areas. Thought and action will automatically reflect policy and measures for the solution of economic ills, because they will draw their strength from the community itself. The altogether untenable divisions of the role and sphere of operation of Khadi and Village Industries Commission, All-India Handloom Board, and Small-Scale Industries Board, may well be replaced by Rural Development Boards, which will provide the right organisational framework for the participation of all economic interests and give any programme the stamp of popular will.

The Commission has, during the past decade, completed the basic organisational and administrative preparation for the implementation of programmes of real purpose and significance. Reconsideration of

its policies governing its programmes, of their techno-economic content and relevance to the establishment and development of a decentralized economic order as an integral and enduring part of the economy, and of the programmes of training and research needed for their effective implementation—is the essential task that awaits a realistic approach.

Social Purpose

As stated at the outset, khadi is not merely a commodity, but a body of basic principles. The so-called sentimental value that attaches to khadi has often been allowed to descend to the level of sentimentality that robs khadi of all its value. Appreciation of the social purpose of khadi, which is the greatest legacy Gandhiji left the nation, can assist in the preparation of a programme of effort that will be economically acceptable to all interests and socially significant to command the willing support and participation of all sections of the population.

Low levels of income of over 60 per cent of our population and the bleak prospect of any immediate improvement in their lot should not lead to programmes of perpetual dependence, or activity that promises no enduring result. Both unfortunately perpetuate the disease in the body, economic and social, and pose a problem of potential political menace. The change that is necessary to remedy the situation has to be large enough to enthuse the people in the present and to encourage them to continue their efforts with assurance of ultimate success. If this article provokes policy-makers into thinking on these lines, this effort will not have been made in vain.

Bombay
21 August 1963

EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT DURING LAST FIFTEEN YEARS

B N DATAR

With successive plans the situation in respect of unemployment has worsened as the development of the economy has been slower than had been visualised. The employment situation and the different aspects of the problem of unemployment during the last decade and a half are discussed in this article

THIRL is hardly any need to emphasise the role of employment in the context of development and planning. Every individual willing to work is affected by the employment situation. If there is no employment for him, he and members of his family have to face hardship in life and the country also suffers a loss because there is consumption without participation in the nation's productive activity. There are a thousand and one occupations in which the workers engage themselves according to their education, training, aptitude and skill. Some of them live in rural areas and others in urban areas and they also migrate from one area to another (generally from village to town) in search of work. Although it looks so natural for an individual to seek work, yet to secure it is not always easy. In fact there is a real struggle for employment, and this makes it a matter of deep and abiding interest to every one right from the politician, economist and planner down to the man in the street.

Economic development and creation of employment opportunities are two aspects of the same process which aims at satisfying the never-ending human aspiration for bet-

ter living standards. The distinction between employment (i.e. in relation to those engaged in work carrying daily or monthly wages or salaries) and unemployment (i.e. in relation to those who had employment but lost it or others who are seeking work) is quite clear. These concepts are associated with wage-paid work and used to describe the situation in developed economies where people are either with jobs or without them.

Causes of Unemployment

Unemployment in a developed economy occurs mainly due to technological changes and is of the frictional type depending on fluctuations in the state of business in its generalised sense and on changes in the level of productivity brought about by rationalisation and application of better techniques of production. In a developing economy the planner has to strike a balance between methods that increase productivity and methods that increase employment. New industries and new projects open up new avenues of employment. In order to ensure continuity of employment and prevent wastage of manpower, deployment arrangements have to be

made. In developing economies one has to think of underemployed persons who are not unemployed but employed with insufficient work and are available for additional work.

Abundance of Manpower

In short, the unemployment problem in the context of conditions obtaining in our country affects a fairly large number of people and for a much larger number only short-term employment is available. The first is typical mostly of urban areas and the second of rural areas although it is difficult to distinguish unemployment from underemployment in the villages. As there is not enough work for everybody offering himself for employment, the limited work opportunities are shared by the working population. This manpower surplus, if mobilised, can make for rapid economic development. The remark that India is a land of poverty in the midst of plenty refers more appropriately, perhaps, to the abundance of one resource, i.e., manpower.

An assessment of the employment situation over a period of the last fifteen years will mean going back to 1947, i.e. the year of India's independence. The main difficulty in this regard is the lack of information and the gaps are too wide to enable anybody to construct a complete picture of the employment, unemployment and underemployment situation. The period between 1947 and 1950 was one of adjustment to partition. The 1951 census may, therefore, be depended upon as the source with which one could start the analysis. But a census is useful only for a study of the employment pattern of the working population.

Employment in Cities

The information about unemployment and that too mainly for urban areas is collected

through the employment exchanges under the National Employment Service. The number of registrants on the live register at the employment exchanges rose from 1.72 lakhs in December 1947 to 2.87 lakhs in December 1950. Interpretation of these figures as an indication of trends in employment and unemployment is governed by a number of limitations, such as location of exchanges only in selected areas, increase in the number of exchanges from time to time, voluntary nature of registration and recruitment through exchanges, the possibility of registration by employed persons for better employment, etc. These figures fail, therefore, to quantify the volume of unemployment even among workers in urban areas. Although details regarding the growth of labour force or data of employment generation during this period are not available, it may not be inappropriate to assume that between 1947 and 1951 unemployment was not an important point in economic debates. The hangover of the Second War and the Korean boom appear to have contributed towards stabilising the employment position to a point of no serious concern.

It may now be worth while to assess the situation in quantitative terms during the First and Second Plan periods. The factors which affect employment in quantitative terms are those relating to (a) numbers unemployed at the beginning of the Plan, (b) addition to the labour force during the Plan period and (c) generation of additional employment opportunities as a result of the implementation of the Plan. The estimates in regard to (c) take into consideration not only the direct employment in the planned sectors of the economy but also the indirect employment opportunities arising in trade, commerce and transport. Addition to labour force is calculated in relation to the propor-

tion of men and women in the age group 15-59 estimated as being gainfully employed or seeking employment

First Plan

The First Plan was formulated to tackle in the main the special problems arising out of the war and partition. For reasons stated earlier, it did not take a serious view of the employment situation. Broadly speaking, the First Plan aimed at strengthening the economy at the base and bringing about institutional changes for accelerating the pace of development in the future. But when the Plan was half-way through, the Planning Commission had to take notice of the problem of unemployment. With the boom conditions due to Korean war disappearing, the number of job seekers on the live register increased to 5.22 lakhs in December 1953. The Plan was, therefore, modified to accommodate special schemes for relieving unemployment. Additional short-term schemes which would encourage employment generation were added to the Plan. The employment content of the First Plan, as originally formulated, was creation of 5.5 million job opportunities outside agriculture

As a result of subsequent adjustments made during the Plan period including the '11-point programme', the employment target of the First Plan was more or less realised. But even this target itself was short of the number of new entrants to the labour force during the First Plan period. The consequent deterioration in employment situation was reflected in the number of registrants on the live register having gone up to 7.05 lakhs in March 1956. The absolute increase during the five year period, i.e., between March 1951 and March 1956 was thus of the order

of 3.68 lakhs. Studying these figures in the context of the results of the National Sample Survey (preliminary survey) of urban unemployment (which established that 25 per cent of the unemployed register themselves with the exchanges) some rough estimates can be made of the magnitude of the urban unemployment prevalent in 1951 and 1956. These would be of the order of 13.48 lakhs and 28.20 lakhs respectively.

Second Plan

On this basis, the Second Plan estimated the backlog of urban unemployment in the beginning of the Second Plan at 2.5 million after making allowance for frictional unemployment which is unavoidable. The backlog of rural unemployment was estimated at 2.8 million on the basis of the Report of the Agricultural Labour Inquiry. Employment became one of the four objectives of the Second Five Year Plan. For a better understanding of the problem, the machinery for collection of regular information regarding employment was considerably strengthened during the period of the Second Plan. New exchanges were set up and a network of Employment Market Information Centres operating through employment exchanges started functioning. The latter source started reporting on the employment situation in the entire public sector and private sector establishments employing 25 or more workers each and yielded valuable information regarding changes in the employment level at various centres.

The Second Plan began with a backlog of 5.3 million unemployed—2.5 million in urban areas and 2.8 million in rural areas. New entrants to the labour force during the Second Plan were reckoned at 10 million. The Second Plan had thus before it the task of providing employment to over 15

million persons if the level of full employment was to be reached. It was recognised that during the plan period, an effort must be made to absorb in employment at least the equivalent of new entrants to the labour force so as to hold the unemployment line. The employment target in the Second Plan was, therefore, placed at 10 millions. It was expected that some measure of relief to the underemployed would come through programmes relating to irrigation, community development, village and small industries, etc. Besides, certain special schemes for educated unemployed were drawn up which included the setting up of work-cum-orientation centres, cooperative goods transport, establishment of production centres, etc.

The plan, however, had to undergo a downward revision in terms of outlay and physical targets which, coupled with an increase in the price level, curtailed the employment content of the plan by about 20 per cent. The result was a further rise in the backlog of unemployed to be carried over to the Third Plan. In spite of a sizable effort at employment generation the first two plans ended with a larger number of unemployed estimated at about 9 million to be taken care of during the Third and subsequent Plans. This number represented about 2.1 per cent of the country's population which was 439 million according to 1961 census.

Third Plan

Besides this backlog, the new entrants to the labour force during the Third Plan period were estimated at 17 millions, which perhaps may even be bigger when revised in the light of the details of 1961 census data which are now under tabulation. Although it is not possible to give a precise estimate of underemployment, its magnitude in relation to

those who have some work but are willing to take up additional work is placed at 15 to 18 millions. This estimate is based on the enquiries conducted by the National Sample Survey during 1955 and 1957 and consists of persons working for four hours or less per day on an average (severely underemployed) and of those working for four to eight hours per day (moderately underemployed) who desire additional work. The employment objective of the Third Plan is creation of 17 million job opportunities which is the expected addition to the labour force.

The Third Plan deals elaborately with the magnitude of the problem in its various aspects and also with the measures envisaged for achieving the employment goal. It aims at creating additional employment potential of 14 millions—10.5 million in non-agricultural occupations and 3.5 million in agricultural and allied activities. Through the rural works programme, it is proposed to create another 2.5 million job opportunities by the last year of the plan in rural areas, but this programme will be more in the nature of relief to the underemployed. Much significance is attached to employment generation from programmes relating to village and small industries, full utilisation of their productive capacity, rural industrialisation, rural electrification, transport, etc.

The Plan also lays stress on the desirability of tackling the employment problem at the district, block and village levels. It has been pointed out as in the past that eradication of unemployment has to be a process spread over a long term. One of such long-term employment objectives, as stated in the Plan, is to reduce the proportion of the working force dependent on agriculture to 60 per cent by 1976. This

implies creation of 50 million employment opportunities in the non-agricultural sector during the period 1961-76

Slow Economic Development

Regarding the employment trend in the first two years of the Third Plan, it may be mentioned that on a rough estimate, additional employment of the order of about four million would have been generated against the annual increase in the labour force of over three millions. Obviously the achievement falls short of our needs. This situation is again reflected in the number of employment seekers at the exchanges. Their number went up from 15.61 lakhs at the end of March 1961 to 18.54 lakhs in March 1962 and to nearly 25 lakhs in March 1963. Even allowing for the opening of more exchanges and the effect of the compulsory notification of vacancies, such big increases are obviously a matter of serious concern.

On the whole, the development of the economy has been much slower than visualised. This is further supported by the national income statistics. Agricultural production has remained almost static and industries are working below capacity due to a number of bottlenecks, such as shortage of power, raw materials, foreign exchange, etc. If population growth continues at the 1951-61 rate and the rate of development does not accelerate in the future, there are reasons to believe that the employment situation will undergo further deterioration during the Third Plan period.

Shortage of Technicians

Simultaneously with the increase in the number of unemployed, however, there are shortages of manpower particularly in regard to technical and professional workers. To some extent these may be due to re-

gional imbalances but, on the whole, they suggest lack of balance, perhaps temporary, between the supply of manpower and the manpower needs of the economy. Accordingly a substantial expansion of technical education and training facilities has been provided for in the Third Plan so as to meet the current requirements and lay the foundation for an adequate supply in future of such personnel at all levels. Building up of trained technical personnel within the country is an important aspect of manpower utilisation. In the short run, it may be possible to carry on with borrowed hands. But since trained manpower is also a scarce commodity in the world market, reliance on its continued import can be considered neither desirable nor feasible.

Educated Unemployed

During the last twelve years public attention has been focussed on another aspect of our employment problem, viz., the educated unemployed. The live registers of the employment exchanges have been showing a large number of educated persons as unemployed. The matter needs investigation. According to the estimates of a Study Group appointed in 1955 which defined educated persons as those who have crossed the matriculation standard, the number of unemployed as at the beginning of the Second Plan was about 5.5 lakhs. The number has considerably increased since. One of the outcomes of this study was the currency it gave to the idea of finding out the relationship between university education and employment so as to discover the direction in which the system of education needs reorientation.

The first step in this direction was a survey undertaken in 1958-59 of the alumni of the Delhi University for the years 1950

and 1954, covering all persons who obtained degrees, diplomas and certificates from the university during those years. Although a high percentage of the alumni appear to have suffered initial unemployment for over a year before getting first employment, their employment position on the whole was not found to be unsatisfactory. The public sector provided jobs to a major portion of them. The survey also revealed a fairly high degree of mobility in search for higher emoluments, better occupational status or a greater measure of security.

Apart from large incidence of vocational aimlessness, there was a strong inclination for following the family pattern in seeking employment. Teaching was the most popular vocation with the women alumni occupying nearly 50 per cent of the posts. The survey established a close relationship between education and employment in regard to technical and professional courses except in the case of law. A large number of persons with general education were found to be working as clerks, thereby revealing an unsatisfactory relationship between general education and employment. General degree-holders also showed a high degree of occupational mobility. Encouraged by the result of the Delhi survey of 1958-59 an all-India survey on the pattern of graduate employment was started in 1960 which was confined to university graduates who obtained degrees in 1950 and 1954. Though final data of this latter survey are not published, the conclusions of the Delhi survey, in the main, seem to be supported by the all-India data.

These surveys and the complementary information regarding the industries to be developed and the estimates of their requirements on the basis of estimated manning patterns will provide suggestions for

a better utilisation of educated manpower. As the plan goes ahead, more and more employment opportunities are also likely to be created for the educated persons to work in the rural areas in the fields of village administration, education, cooperation, transport, rural industries, etc. Creation of more employment opportunities combined with a change in their attitude towards manual work will go a long way to solve their problem.

Deterioration in Situation

From what is stated above it will be seen that

(i) The employment problem in India consists of both unemployment and under-employment—the former prevails mainly in urban areas and the latter in rural areas.

(ii) Since independence upto 1951 employment was not an important point in economic debates because of the favourable impact of the Second War and the Korean boom.

(iii) In spite of developmental efforts under the first two and the third plans, employment situation has been showing signs of deterioration, because employment opportunities are not being created at a rate fast enough to absorb new entrants to the labour force.

(iv) Paradoxically, with abundant manpower, the economy has been experiencing shortages of manpower especially in regard to technical and professional personnel which implies, perhaps temporarily, lack of balance between the supply of manpower and the manpower needs in the country.

(v) Side by side, with increase in the volume of general unemployment, incidence of unemployment among the educated job-seekers has also been rising.

New Delhi
7 September 1963

INVESTMENT AND CAPITAL ACCUMULATION IN INDIA

AMRITA DALLA

The rate of increase in gross fixed investment has been faster since independence than that of gross national product. The annual rate of increase of capital accumulation has also exceeded that of net fixed investment. This has synchronised with a high incremental capital—output ratio. This article points to the need for maximising export earnings which alone can speed up the process of fixed capital formation in the country.

THE growth of capital formation in India has been slow. Except for the establishment of the jute and cotton textile industries which involved large-scale investment in the nineteenth century industrial development in this country was virtually at a standstill until the twenties of this century. The twenties witnessed the establishment of a few industries for the manufacture of consumer goods and intermediate products. This process gained some momentum during the war and early post-war period and even a beginning was made to establish a few capital goods industries viz., diesel engines, locomotives, textile machinery, etc. However, investment was not only concentrated on consumer goods industries but was controlled and managed almost entirely by private enterprise. The scope for the expansion of the capital goods sector was limited due to the operation of several well-known inhibiting factors. As a result, the resources allocated to fixed investment were relatively nominal.

The long period of stagnation in fixed capital formation came to an end with the coming

This article is written by the author in his personal capacity.

of independence. The period following August 1947 marked the inception of a vigorous phase in the economic development of India. With the change in industrial policy and commencement of the five year plans, governmental policy was increasingly orientated towards an expansion of fixed investment for achieving a high rate of economic growth. An idea of the rapid advance made by the country in recent years could be had from the growth in fixed capital formation since independence. Between 1948-49 and 1960-61 while gross fixed investment rose at an annual rate of seven per cent, the annual rate of increase witnessed in respect of the public sector was 13 per cent as against 5.6 per cent in respect of the private sector. Besides, the share of the public sector in gross fixed investment (at 1958-59 prices) increased from 19.3 per cent in the pre-Plan period to 27.3 per cent and 33.5 per cent in the First and Second Plan periods respectively. Associated with this increase in the volume of investment was the rise in the share of gross fixed investment in gross national product (i.e. average investment ratio). As the following figures show, the average investment

ratio increased from 12.1 per cent in the pre-Plan period to 13.2 per cent in the First Plan period and to 17.5 per cent in the Second Plan period *

	Annual Rate of Growth in Gross Fixed Investment (percentage)	Average Investment Ratio
	(at 1958-59 prices)	
Pre-Plan period (1948-49 to 1950-51)	4.1	12.1
First Plan period (1951-52 to 1955-56)	8.6	13.2
Second Plan period (1956-57 to 1960-61)	6.5	17.5
Entire period (1948-49 to 1960-61)	7.0	14.8

Source: Central Statistical Organisation, Government of India and *Economic Survey of Asia and the Far East*, United Nations, 1961

The allocation of resources for investment, of investment ratio which remained more or however, did not strictly follow the plan less stable until 1954-55 but registered a per- periods This could be seen from the trend ceptible increase thereafter As figures in

TABLE 1
GROWTH OF PUBLIC AND PRIVATE INVESTMENT
(At 1958-59 prices)

Year	Ratio of Gross Fixed Investment to Gross National Product			Public Invest- ment As Percentage of Total Investment
	Public	Private	Total	
1948-49	2.1	9.5	11.6	17.9
1949-50	2.3	10.1	12.4	18.9
1950-51	2.6	9.7	12.3	21.0
1951-52	2.9	10.0	12.9	22.3
1952-53	2.9	9.2	12.1	24.0
1953-54	3.2	8.6	11.8	27.2
1954-55	3.8	9.4	13.2	29.2
1955-56	5.0	10.6	15.6	31.8
1956-57	5.4	11.9	17.3	31.1
1957-58	5.4	13.3	18.7	29.0
1958-59	5.3	11.3	16.6	32.1
1959-60	7.3	10.8	17.1	42.8
1960-61	5.8	12.0	17.8	32.4

Source: Data on fixed investment have been taken from the Central Statistical Organisation paper and those on gross national product from the *Economic Survey of Asia and the Far East* 1961. The latter have been compiled from the former.

* Throughout this article, data on fixed investment, stocks and other allied data have been taken from the Central Statistical Organisation paper on National Income Statistics (Estimates of Gross Capital Formation in India, 1948-49 to 1960-61).

Table 1 show, the average investment ratio at constant prices improved from 12.3 per cent during 1948-49 to 1954-55 to 16.6 per cent during 1954-55 to 1960-61. From 1954-55 onwards, not only public outlay was accelerated but there was also increased activity in the private sector which had emerged more confident from the climate of uncertainty (i.e. threat of nationalisation, labour troubles etc.) of the early post-independence period. Moreover, since 1954-55, there had been a greater rate of increase in gross fixed investment than in the growth of gross national product. While the average rate of increase in fixed investment was 5.3 per cent from 1948-49 to 1954-55 and 8.7 per cent from 1954-55 to 1960-61, the corresponding average rates for gross national product were 2.9 per cent and 3.1 per cent respectively. The year

1954-55 may, therefore, be taken as the dividing line for purposes of study.

Progress of Public Sector

Of the two sectors which contributed to the growth of fixed investment in India, the private sector, as its past legacy indicated, no doubt contributed the major share (10.5 per cent) of gross national product as against a relatively small share (4.3 per cent) of the public sector. However, as already stated above, the annual rate of rise in fixed investment in the public sector was much higher than that witnessed in respect of the private sector though in the second half of the period under review, the rate of increase of the former somewhat slowed down while that of the latter improved sharply. None the less the overall high rate of increase witnessed

TABLE 2

RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH IN GROSS NATIONAL PRODUCT AND GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

(At 1958-59 prices)

Annual Rate of Growth (Percentage)	1948-49 to 1960-61	1948-49 to 1954-55	1954-55 to 1960-61
Gross National Product (GNP)	3.0	2.9	3.1
Gross Fixed Investment	7.0	5.3	8.7
(i) Public Sector	13.0	14.2	11.8
(ii) Private Sector	5.6	2.7	8.5
Gross Fixed Investment as Percentage of G.N.P.	14.8	12.3	16.6
of which (i) Public Sector	4.3	2.9	5.5
(ii) Private Sector	10.5	9.4	11.1
Incremental Capital-Output ratio*	4.9	4.2	5.4

* Obtained by dividing the average investment ratio by the annual rate of growth in gross national product.

in respect of the public sector during the period under review is enough proof (if proof were at all needed) of the significant progress made by this sector since independence. Its relatively low investment ratio may still be considered impressive in the context of the almost stagnant conditions in public economic activities prevalent in the thirties.

Gross and Net Investment

At this stage it may be interesting to study the changes in the relationship between gross and net fixed investment, depreciation and changes in inventories during the period under review. Although some adjustments have been made in the data presented in table 3 (as mentioned in the footnote), it may be

assumed that the trends are not likely to be affected by this adjustment. It may be seen from table 3 that both gross fixed investment and capital accumulation reacted evenly during the period under review. As a ratio to gross national product, both gross and net fixed investment rose from 12.3 per cent and 5 per cent respectively in the first half to 16.6 per cent and 10.1 per cent in the second. The growth in capital accumulation also occurred in the same direction from 6.3 per cent to 11.6 per cent in the corresponding period. The differences between the changes in capital accumulation and changes in net fixed investment were due to fluctuations in stocks which rose from 1.3 per cent to 1.5 per cent. This was at-

TABLE 3

RELATIVE CHANGES IN GROSS FIXED INVESTMENT, DEPRECIATION, INVENTORY AND CAPITAL ACCUMULATION AS PERCENTAGE OF GROSS NATIONAL PRODUCT

(At 1958-59 prices)

Period	Gross Fixed Investment	Depreciation	Net Fixed Investment	Inventory Change	Capital Accumulation
1948-49 to 1950-51	12.1	7.6	4.5	1.1	5.6
1950-51 to 1952-53	12.4	7.3	5.1	1.0	6.1
1952-53 to 1954-55	12.4	6.9	5.5	1.1	6.6
1954-55 to 1956-57	15.4	6.7	8.7	1.8	10.5
1956-57 to 1958-59	17.5	6.5	11.0	1.7	12.7
1958-59 to 1960-61	17.2	6.4	10.8	2.1	12.9
1948-49 to 1960-61	14.8	6.9	7.9	1.4	9.3
1948-49 to 1954-55	12.3	7.3	5.0	1.3	6.3
1954-55 to 1960-61	16.6	6.5	10.1	1.5	11.6

Note As the figures for net fixed investment are available only at current prices, the proportion of net fixed investment to gross fixed investment for each year at current prices has been applied to gross fixed investment at constant (1958-59)

prices in order to arrive at net fixed investment at constant prices

Source Central Statistical Organisation, Government of India

tributable mainly to the uncertainty of harvests in the country necessitating an increase in foodstocks through imports

Depreciation Ratio

The large differences between the percentages of gross and net fixed investment to gross national product reflected changes in depreciation which was reduced from 7.3 per cent in the first half to 6.5 per cent in the second. While, over the period as a whole, net fixed investment increased at a much higher rate (13.7 per cent) than gross fixed investment (7 per cent), depreciation

rose at an insignificant rate of 1.2 per cent per annum (table 4). The ratio of depreciation to gross national product was higher than that of net fixed investment in the first half but fell below the latter in the second. The relatively lower ratio of depreciation reflected greater longevity of capital assets. A greater volume of obsolescence of plant and machinery had to be reckoned with in the first half following the legacy of war-time worn-out plants than in the second when synchronising with the Second Plan period, new plants and machinery were established in the public sector.

TABLE 4

RATE OF INCREASE IN GROSS FIXED INVESTMENT, DEPRECIATION, NET FIXED INVESTMENT AND CAPITAL ACCUMULATION

(Percentage At 1958-59 prices)

	1948-49 to 1960-61	1948-49 to 1954-55	1954-55 to 1960-61
Gross Fixed Investment	7.0	5.3	8.7
Depreciation	1.2	1.1	1.3
Net Fixed Investment	13.7	12.3	15.2
Accumulation	15.4	14.2	16.6

Source: Central Statistical Organisation, Government of India

Capital Accumulation

It is interesting to note that capital accumulation not only showed a rise in the second half but its annual rate of increase even exceeded that of net fixed investment. The changes in inventories were rather insignificant though there was a slight increase in stocks in the second half over the first. This showed the inability of the industrial sector to keep more stocks than were ab-

solutely necessary. For it was not always possible to build up inventories due mainly to the operation of rigorous import control and allotment of quotas for raw materials on a restricted scale following the foreign exchange crisis of 1957. Moreover, the market was highly protected through import control, tariffs and other devices which enabled the manufacturers to dispose of their stocks quickly at high profits. However, even the

small increase in stock formation in the second half reflected, as already explained above, an increase in the central reserves to meet emergencies on the food front. The ratio of total stocks of foodgrains to available supply rose from six per cent during 1948-49 to 1954-55 to 16 per cent during 1954-55 to 1960-61 (for details, see table 10). However, in spite of the slight increase in stocks, capital accumulation witnessed a sharp rise in the second half. Thus, the employment of an increasing proportion of resources has stimulated investment and led to a rapid growth of the economy during the brief period of 13 years since independence. While both the public and private sectors have contributed to the expansion, the rate achieved by the former has been quite impressive.

High Capital-Output Ratio

The substantial growth in capital accumulation has synchronised with a high incremental capital-output ratio during the period under review. As figures in table 2 show, the incremental capital-output ratio increased from 4.2 in the first half to 5.4 in the second and was associated with an increase in the ratio of fixed investment to gross national product from 12.3 to 16.6 in the corresponding period. It is a well-known fact that both industry and agriculture operated much below capacity levels in the early post-independence period and that there were frequent scarcities of goods and services. Although over the years, the position improved in regard to available supplies, demand for them has increased much more. Both domestic and international demand has accounted for an expansion of supplies for domestic consumption and for pur-

poses of export. However, because of the slow growth of the export sector and consequent slow rise in exports, an increase in investment either in this particular sector or in other fields has accounted for an increase in the capital-output ratio, especially in the second half. Moreover, investments in new fields have taken time to materialise and while gross fixed investment has increased, as already pointed out, at a fast annual rate, gross national product has advanced rather slowly. Naturally, therefore, the growth in supplies has been inadequate from a long-term point of view.

II

Domestic Real Resources

The sharp increase in the volume of investment has been accompanied and at times facilitated by an increase in the volume of real resources to meet the diverse needs of domestic capital formation. This has been brought about in two ways. Domestic output of some basic industries, namely, cement, has progressed to such a significant extent as to minimise or eliminate imports altogether. On the other hand, imports of some commodities, namely, iron and steel or capital goods have been allowed to help in the process of fixed capital formation. The extent of dependence on domestic output and/or imports may be seen from table 5. Domestic production of all the main items under 'Construction', such as cement, iron and steel made substantial progress though imports of iron and steel and other building materials (excluding cement) were still necessary to augment domestic resources, especially in the second half. Although domestic output of capital goods and other machinery registered an improvement,

TABLE 5

DOMESTIC PRODUCTION AND IMPORTS OF CONSTRUCTION MATERIALS
AND MACHINERY AND EQUIPMENT AS PERCENTAGE OF GROSS
FIXED CAPITAL FORMATION

(At current prices)

	1948-49 to 1960-61		1948-49 to 1954-55		1954-55 to 1960-61	
	Pro- duction	Import	Pro- duction	Import	Pro- duction	Import
(1) Construction Materials	19.5	2.7	20.4	1.9	19.2	3.0
of which						
Cement	3.2	0.1	2.7		3.5	
Iron and steel	5.9	1.5	5.2	0.5	6.3	2.0
other building materials	10.4	1.1	12.5	1.4	9.4	1.0
(2) Machinery and Equipment	13.0	15.1	11.3	15.1	13.9	14.9
of which						
Capital goods	8.1	8.2	7.2	10.2	8.6	7.1
Other machinery	4.9	6.9	4.1	4.9	5.3	7.8
(3) Total (1 plus 2)	32.5	17.8	31.7	17.0	33.1	17.9

Source Central Statistical Organisation, Government of India

imports were understandably much higher with the result that they constituted 15 per cent of gross fixed investment during the period under review.

Construction Materials

Thus, while the expansion in the output of construction materials played a significant part in the growth of fixed capital formation, capital goods and other machinery were augmented through imports due naturally to the absence of a capital base in the country. It is, however, significant that

domestic production in the latter case revealed a significant improvement inasmuch as it constituted 13 per cent of gross fixed investment during the period. In reality, the annual rates of increase in the output of cement and capital goods have been much higher than those of their available supply (table 6). Although the rates of growth in respect of iron and steel and machinery parts were impressive, imports of these two items rose sharply during the period. On the other hand, import of cement witnessed an annual rate of decline (1.4 per cent)

TABLE 6

ANNUAL RATES OF INCREASE/DECREASE IN AVAILABLE SUPPLY,
PRODUCTION AND IMPORTS OF CONSTRUCTION MATERIALS
AND MACHINERY AND EQUIPMENT

(Percentage at current prices)

	1948-49 to 1960-61			1948-49 to 1954-55			1954-55 to 1960-61		
	Avail- able Supply	Pro- duc- tion	Import	Avail- able Supply	Pro- duc- tion	Import	Avail- able Supply	Pro- duc- tion	Import
<i>Construction Materials</i>									
Cement	17.1	18.2	-1.4	18.2	20.5	-0.3	16.1	15.9	-2.5
Iron and Steel	16.5	15.2	40.8	12.5	12.5	19.2	20.6	17.8	62.5
Others	5.0	5.1	7.0	2.5	2.2	9.9	7.5	8.0	4.1
Total	9.6	9.6	17.2	6.3	6.7	8.4	12.9	12.4	26.0
<i>Machinery and Equipment</i>									
Capital goods	8.6	12.6	5.4	4.3	8.7	1.3	13.0	16.5	9.4
Other machinery	19.5	13.5	17.9	7.0	6.5	7.7	32.0	20.5	28.0
Total	11.1	12.8	9.8	4.9	7.6	2.9	17.3	17.9	16.7
Grand Total	10.3	10.7	10.3	5.4	6.9	3.2	15.3	14.5	17.3

Source: Central Statistical Organisation, Government of India

Both production and imports (except for cement) rose sharply in the second half and the resources obtained through imports, especially of iron and steel and machinery parts far outweighed those augmented through domestic output. Generally speaking, while imports of total construction materials rose at a faster rate annually than those of machinery, equipment during the period under review, both production and

available supply of the latter increased at a faster rate than those of the former

Increased Tempo of Investment

As would be expected, capital formation in construction constituted the major share (63.2 per cent) in gross capital formation and gross national product (10.3 per cent) as against 27.9 per cent and 4.5 per cent respectively for machinery and equipment

TABLE 7

ANNUAL RATE OF INCREASE AND RELATIVE SHARES OF FIXED INVESTMENT IN 'CONSTRUCTION' AND 'MACHINERY AND EQUIPMENT' IN GROSS CAPITAL FORMATION AND GROSS NATIONAL PRODUCT

(At 1958-59 prices)

Gross Fixed Investment in	Relative Shares in		
	Annual Rate of Increase	Gross Capital Formation	Gross National Product
<i>Construction</i>			
1948-49 to 1960-61	7.2	63.2	10.3
1948-49 to 1954-55	7.5	63.0	8.6
1954-55 to 1960-61	6.9	63.7	11.6
<i>Machinery and Equipment</i>			
1948-49 to 1960-61	6.9	27.9	4.5
1948-49 to 1954-55	0.5	27.3	3.1
1954-55 to 1960-61	13.2	27.9	5.1
<i>Gross Fixed Investment</i>			
1948-49 to 1960-61	7.0	91.1	14.8
1948-49 to 1954-55	5.3	90.3	11.7
1954-55 to 1960-61	8.7	91.6	16.7

Source Central Statistical Organisation Government of India

during the period (table 7). The relative shares of construction and machinery and equipment in gross national product showed two distinctive trends between the first and the second half. As seen in table 7, the ratios were low in the first half but rose substantially in the second. The same tendency was witnessed in respect of total gross fixed investment vis-a-vis gross capital formation and gross national product. Although the ratio remained at about 91 per cent relatively to gross capital formation in both the half-periods, it moved from 12 to 17 per

cent relatively to gross national product during the same time-interval. Such an abrupt swing may be attributed to the generally increased tempo of investment activity during the second half of the period under consideration.

The annual rates of increase of these items at constant prices revealed sharp variations during the period. While the fixed investment in construction was reduced from an annual rate of 7.5 to 6.9 per cent that in respect of machinery and equipment jumped from 0.5 to 13.2 per cent during

the two halves. The insignificant increase witnessed in the first half is mainly attributable to the lack of availability of capital goods abroad in the early post-war period. At any rate,* the investment programme in the country had not been intensified before 1954-55 to account for a sizable increase in the annual rate of fixed investment in machinery and equipment. With the investment programme gaining momentum in the second half, the annual rate of increase in this sector recorded a sharp improvement. As a result, total fixed investment also increased at an annual rate from 5.3 to 8.7 per cent in the corresponding period.

On the whole, however, the expansion of machinery and equipment has been small relatively to that of building materials during the period. In reality, all the major expansion in gross fixed investment has been facilitated by an increase in imported sup-

plies. In the second half of the period particularly, the import content of investment witnessed a sharp increase. Although it was accompanied by a high rate of production of iron and steel, capital goods and other machinery parts, imports of these very items witnessed a much faster rise in the second half than in the first. Thus, an expansion in gross fixed investment has been supported both by a rise in domestic output leading to import substitution (as in the case of cement) and a greater volume of imports (as in the case of iron and steel and capital goods). The question now arises whether import capacity has been adequate to facilitate this increase in imported supplies.

III

Import Capacity

At the beginning of April 1948, the foreign exchange resources of the country

TABLE 8

INDICES AND ANNUAL RATES OF INCREASE/DECREASE IN REAL IMPORTS AND IMPORT CAPACITY

(At 1958-59 prices)

(Base 1948-49 to 1954-55 equal to 100)

	1948-49 to 1960-61		1948-49 to 1954-55		1954-55 to 1960-61	
	Indices	Annual Rate	Indices	Annual Rate	Indices	Annual Rate
Real Merchandise Imports*	125.3	9.8	100.0	7.5	146.9	12.1
<i>Import Capacity derived from</i>						
Exports and net services	105.5	6.1	100.0	10.8	116.1	1.4
plus official loans and grants	116.6	8.2	100.0	9.1	131.1	7.3
plus other long-term capital	121.6	8.0	100.0	6.6	140.2	9.4
Foreign Exchange Reserves	81.9	-8.2	100.0	-4.9	64.8	-11.6

* Excludes the extraordinary payment of Rs 71.9 crores to the UK in 1948-49 for the purchase of defence stores and installations.

† Excludes silver despatched to the USA

valued at Rs 74.4 crores in 1957-58 in payment of lend-lease obligations. 'Net services' exclude 'official' but include 'private' donations.

Source: Reserve Bank of India.

amounted to Rs 1,612 crores which were reduced to Rs 910 crores by the beginning of April 1954 and subsequently to Rs 363 crores by the beginning of April 1960. Although import capacity derived from merchandise exports and net services showed an improvement in the second half, resource had to be taken to foreign exchange reserves to finance the import content of fixed investment. Between the first and the second half, as figures in table 8 show, import capacity derived from merchandise exports and net services increased by 16.1 per cent which coupled with official loans and grants went up by 31.1 per cent and together with other long-term capital witnessed a further rise by 40.2 per cent. As a matter of fact, official loans and grants together with other long-term capital accounted for 23.7 per cent of total foreign exchange receipts during the period though as between the two halves, the variation was considerable from

11.9 per cent to 30.8 per cent. However, real merchandise imports registered an increase by 46.9 per cent during the corresponding period.

This excess of imports over import capacity was of course financed by foreign exchange reserves though the import equivalent of exchange reserves was drastically reduced by 35.2 per cent in the second half compared with the first. While merchandise imports increased at a faster rate (9.8 per cent) than import capacity (8 per cent), the only alternative to finance the resultant deficit was to take recourse to foreign exchange reserves. Especially in the second half real imports increased at a much higher rate (12.1 per cent) than the total import capacity (9.4 per cent) with the result that foreign exchange reserves were reduced at an annual rate of 11.6 per cent. Thus, real imports did not have to depend entirely on total import capacity for financing the

TABLE 9
IMPORTS OF CAPITAL GOODS, RAW MATERIALS AND CONSUMER GOODS
AS PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS
(At current prices)

Period	Total Imports	Capital Goods*	Raw Materials	Consumer goods	
				Food	Total
1948-49 to 1950-51	100.0	25.8	29.8	16.5	23.8
1950-51 to 1952-53	100.0	22.6	31.1	20.2	26.9
1952-53 to 1954-55	100.0	27.1	28.9	14.6	22.5
1954-55 to 1956-57	100.0	35.7	23.1	4.0	13.2
1956-57 to 1958-59	100.0	40.4	18.2	8.8	18.6
1958-59 to 1960-61	100.0	38.5	18.6	17.6	26.4
1948-49 to 1960-61	100.0	32.5	24.2	13.7	22.0
1948-49 to 1954-55	100.0	24.8	29.9	17.1	24.4
1954-55 to 1960-61	100.0	38.0	20.3	10.6	19.8

* Figures for capital goods given here are slightly different from those given by the Central

Statistical Organisation Paper
Source Reserve Bank of India

import content of domestic fixed investment

Alteration in Composition

An increase in gross fixed investment consequent on a rise in imports of capital goods and machinery parts has involved an alteration in the composition of imports as well. Imports of capital goods, as figures in table 9 show, witnessed an increase from 25 to 38 per cent between the two halves whereas those of raw materials and consumer goods declined perceptibly from 30 and 24 per cent to 20 per cent each respectively in the corresponding period. The main factor behind this phenomenon was the rigorous control over imports which was especially tightened up following the foreign exchange crisis in 1957. While increased imports of capital goods helped in the process of fixed capital formation, there was at the same time a reduction in the imports of raw materials and consumer goods as a ratio of total imports. To the extent the maintenance

of industrial activity in the country was concerned, restrictions placed on the import of raw materials were a disconcerting feature as it was likely to retard the growth of the economy and of fixed investment itself.

Foodgrains

On the other hand, restrictions imposed on the imports of consumer goods in general have been a usual feature of our import trade though food imports in large quantities have been necessary following poor harvests off and on. Indeed, the ratio of foodgrains to total imports of consumer goods amounted to 62 per cent during the period though it was reduced from 70 per cent in the first half to 54 per cent in the second. Although production of foodgrains increased by 20 per cent in the second half, increased imports were necessary not only to satisfy domestic consumption but also to build up reserves. As figures in table 10 show, although domestic consumption of foodgrains increased at 2.5 and 2.7 per

TABLE 10

POSITION OF FOODGRAINS IN INDIA

Period	Annual Rate of Growth (Percentage)			Net Imports as % of Consumption		Stocks as % of Available Supply
	Domestic Production	Net Imports	Total Consumption	Human	Total	
1948-49 to 1960-61	3.4	12.5	2.6	4.5	4.1	11.5
1948-49 to 1954-55	3.7	-3.9	2.5	5.2	4.7	6.1
1954-55 to 1960-61	3.2	28.9	2.7	3.4	3.1	16.0

Note: Figures are originally in thousand tons and are taken from the Central Statistical Organization paper referred to earlier.

cent annually in the first and second half respectively, the corresponding rates of rise in foodgrain production were higher at 3.7 and 3.2 per cent respectively. The share of net imports in consumption (both human and total) actually fell in the second half and in any case constituted a small percentage (3 to 5 per cent). Yet net imports which declined at the rate of four per cent per annum in the first half increased at the rate of 29 per cent per annum in the second accounting for a sharp increase (from 6 to 16 per cent) in the ratio of food

stocks to total availability. In value terms, however, the share of food imports as also of total consumer goods witnessed a decline in the second half and this, coupled with a reduction in the imports of raw materials, accounted for an increase in the ratio of capital goods to total imports.

Raw Materials and Consumer Goods

In reality, the relative shares of imports of raw materials and consumer goods (including foodgrains) in private and total consumption expenditure were reduced in the

TABLE 11
IMPORTS OF RAW MATERIALS AND CONSUMER GOODS AS PERCENTAGE
OF DOMESTIC CONSUMPTION EXPENDITURE
(At current prices)

Imports	1948-49 to 1960-61		1948-49 to 1954-55		1954-55 to 1960-61	
	Private	Total	Private	Total	Private	Total
Raw Materials	20.5	19.0	23.4	21.9	18.1	16.6
Consumer Goods	18.1	17.3	19.1	17.9	17.6	16.2
of which						
Food grains	11.5	10.7	13.4	12.6	9.5	8.7
Total	39.1	36.3	42.5	39.8	35.7	32.8

Note. Figures of domestic consumption expenditure are inclusive of those for goods and services. Total consumer expenditure refers to private and government expenditures at current prices. Several adjustments have been made to compile these figures. As the figures for private current expenditure are merged with those of private net capital formation in the statements showing 'expenditure generating net national product' (see *Estimates of National Income* by CSO), the proportions of private capital formation to total gross capital formation for each year from 1948-49 to 1954-55 have been applied to net capital formation at current prices (available in the

CSO paper) in order to arrive at private net capital formation at current prices. The figures thus derived have been deducted from the merged figures in order to arrive at the figures for private current expenditure on goods and services at current prices.

For the years from 1955-56 to 1960-61, figures for private consumer expenditure have been extracted from the figures on gross national product by rearrangement of data available in the CSO paper. Import figures for raw materials and consumer goods have been taken from the Reserve Bank of India.

second half compared with the first (table 11). The figures of domestic consumer expenditure given in table 11 are, however, tentative and are also inclusive of expenditure on services. It has not been possible to isolate the figures of consumption expenditure for commodities alone. None the less, the broad trends that are discernible unmistakably point towards a decline in these ratios which occurred more especially in respect of raw materials than in respect of consumer goods. In spite of a sharp reduction in the ratios of foodgrain imports to private as well as total consumption expenditure in the second half, the ratios of imports of total consumer goods were only slightly reduced. Although this particular category was subjected to the most rigorous import control, relaxations were made often-times in respect of certain types, viz., electrical goods imports of which witnessed an increase in the second half.

On the other hand, as figures in table 11 show, the ratios of raw material imports to consumption expenditure fell rather sharply in the second half. This was accomplished more by import control and quota allocations than by the free play of market forces. It was really an unreal situation in the context of acute shortage of imported raw materials in certain sectors of the economy. No doubt, both agricultural and industrial production had increased remarkably in the second half over the first. The average index of agricultural production (base 1949-50 equal to 100) had increased from 104.3 during 1949-50 to 1954-55 (year ended June) to 125.1 during 1954-55 to 1960-61 showing an upward movement by about 20 per cent. The annual average index of industrial production (base 1951 equal to 100) had similarly gone up by 37.4 per cent from 103.3 in the first half to 141.9 in the

second. All this improvement should have accounted for a substantial reduction in the ratio of raw material imports to domestic consumer expenditure. Yet, several industries were utterly dependent on imported raw materials not only to operate their plants at optimum efficiency but also to maximise output within the capacity licensed.

Relationship

At any rate, capital goods, raw materials and foodgrains have been the three main rivals in our import trade and a rise in the imports of capital goods has normally synchronised either with a fall in the imports of raw materials or of foodgrains or of both. As figures in table 9 show, imports of capital goods have usually varied inversely with those of raw materials and consumer goods (especially of foodgrains). A decline in the relative shares of raw materials and consumer goods has been accompanied by an increase in the share of capital goods. Thus, in so far as imports of capital goods have determined the level of fixed investment, the latter has been ultimately conditioned by the scarcity of foodgrains and/or raw materials. The main inhibiting factor has been deficiency in food production and the virtual impossibility of curtailing imports of essential raw materials and consumer goods.

Share of Capital Goods

An increase in gross fixed investment was facilitated when import capacity rose at a higher annual rate than private or total consumption expenditure (table 12). This was actually accentuated in the second half though the tendency was visible in both the half-periods. Although real imports rose at a much faster rate than import capacity, the large accumulation of sterling balances

TABLE 12

ANNUAL RATE OF INCREASE IN GROSS FIXED INVESTMENT, REAL IMPORTS, IMPORT CAPACITY AND DOMESTIC CONSUMER EXPENDITURE

(Percentage At 1958-59 prices)

Period	Gross Fixed Investment	Real Import	Import Capacity	Domestic Consumer Expenditure*		
				Private	Government	Total
1948-49 to 1960-61	7 0	9 8	8 0	2 5	4 5	2 6
1948-49 to 1954-55	5 3	7 5	6 6	2 2	2 6	2 2
1954-55 to 1960-61	8 7	12 1	9 4	2 7	6 3	3 0

* The proportions of private and government current expenditure on goods and services to gross national product at current prices arrived at in the way given in footnote to table 11 above have been applied to gross national product at 1958-59 prices in order to arrive at private and government current expenditure at constant prices. The

figures are necessarily tentative and as usual in the case of goods and services. It has not been possible to isolate the two. It is assumed that the broad trends would be discernible even within a small margin of error.

Sources: Central Statistical Organisation and *Economic Survey of Asia and the Far East*, 1961

available at the end of the war was able to finance the gap for a long time. Thus, an increase in import capacity supplemented by a reduction in the import content of domestic consumption enabled the country to raise its share of capital goods in total imports and give an impetus to gross fixed investment. Naturally, therefore, the growth in gross fixed investment varied directly with that of import capacity though the annual rate of growth of the latter was much faster than that of the former. This strange phenomenon may be attributable to the large sums of unutilised official loans and grants from abroad which could not be spent either in the requisite quantity or within the stipulated time. Besides, a sizable portion of the grants was meant to cover food imports on government account and was perhaps

not intended to finance the growth of fixed investment in the country.

Structural Maladjustment

In conclusion, it may be stated that the post-independence period has witnessed a remarkable rate of growth in capital accumulation which has been accomplished mainly by an increase in fixed investment through governmental initiative. The private sector has also played a significant role in the growth of fixed capital formation. Although domestic output has helped in certain directions, the main channel through which resources have been obtained to meet the requirements of fixed investment has been the import trade. This has been facilitated, to some extent, by an increase in import capacity which has risen faster than

domestic consumption expenditure. Yet, real imports have gone up still faster than import capacity necessitating a recourse to foreign exchange reserves. The main factor which has held up progress in fixed investment has been import of capital goods which has been dependent on the relative importance of raw materials and foodgrains in the import trade. Although production in both the agricultural and industrial sectors has risen, it has been hard to restrict the imports of essential consumer goods in general and of foodgrains in particular. Restrictions placed on the import of raw materials have accounted for the slowing down of progress in certain sectors of the economy. Thus, the basic structural maladjustment of the economy still remains—a scarcity in the supply of resources relatively to the overall requirements of economic growth.

For a long time foreign exchange resources

could finance the deficit caused by the excess of real imports over import capacity. With the sharp reduction in reserves in recent years, it will no longer be possible to depend exclusively on these resources. Next come the resources obtained from abroad in the form of official loans and grants but the former has its own problems of repayment and consequent pressure on the balance of payments and the latter cannot obviously continue for ever. All this points to the need for maximising export earnings which alone can speed up the process of fixed capital formation in the country. An acceleration of the rate of fixed investment would undoubtedly involve hardships all round but these have to be borne with patience and fortitude by all. For, the problem of capital accumulation is neither a temporary one nor for that matter a side issue.

Bombay
5 September 1963

The contemporary arguments for moral and intellectual freedom contain little that is new. When a government makes what appear to be unusual or exaggerated efforts to standardize belief and conduct, then we find, for the most part, restatements of the classic arguments of Luther, Milton, Locke, Spinoza, Fenelon, Montesquieu, Voltaire and Mill. Matters of belief, these men maintained, can be determined only by the powers of rational persuasion or by divine revelation and inspiration, coercive efforts to establish uniformity in morals and opinions are sure to fail, man has a natural right to be free in matters of opinion and private morals, and peace and happiness flow from a policy of toleration.

Francis W. Coker *Recent Political Thought*

VILLAGE INDUSTRIES IN TRIBAL AREAS

B H MITTAL

The approach to the development of cottage and village industries in tribal areas cannot be separated from the general approach to the problem of economic development of tribal areas as a whole. The tribals are rich in natural resources and skills and have an aesthetic sense. What is required to set the tribal economy on the road to progress is to give proper training to the local people and to exploit the natural resources.

THE direction, nature and tempo of economic development cannot be the same in all regions, but wherever there is leadership, educational progress and developed communications, the rate of progress can be rapid. Wherever these three factors are absent, or are present in a limited way, progress will be extremely slow and even negligible. The sylvan areas of India, mostly inhabited by more than 30 million tribals, are witnessing a new approach to development. Unfortunately the development agencies do not possess adequate information and knowledge about the natural resources of the physical regions or the inhabitants of such areas. The normal pattern of rural development cannot be easily introduced in tribal areas, and though the community development projects have been recently introduced in the multipurpose project areas, they have not been able to deal with the complex problems that must be dealt with to achieve an intensive development of forest economy.

Valley Section Theory

The role of cottage and village industries in tribal areas cannot be separated from the

general approach to the problem of economic development of tribal areas as a whole. Besides the problem of economic development of tribal areas is very much related to the nature of the land problem and the prevailing pattern of agriculture in the areas, and the manpower situation in these undeveloped and usually underpopulated regions. In the first instance, intensive efforts are needed to study the sylvan economy and notice the important differences that exist between rural and sylvan economy. The differences are well explained by the Valley Section Theory, according to which, physical regions can be broadly divided into six major types: (1) mountain and forest areas, (2) steppe lands and predominant grass lands, (3) plains with their different soil content and irrigation facilities, (4) garden lands and river valleys with their fertile soil and irrigation facilities, (5) the shores and the coast-lines with opportunities for commerce, and (6) deserts with their severe handicaps. Programmes for the development of village industries will greatly benefit if plans are based on a study of petrology and natural resources of the region and the

special characteristics that will affect the people and their economy

The tribal areas are invariably associated with mountainous and forest regions, and sometimes large areas of grass lands are also involved, especially near the foothills of the mountain ranges. Compared to the usual plain areas, these areas have better and more varied natural resources. Some of them have the most valuable and rare raw materials for national and industrial development.

Historically the tribal areas were the habitat of hunters who developed a flourishing economy. The great value of the animal world was well-known to the hunters. The animals in the forests can yet make a contribution to local and national economy. They could help man in augmenting the food supply of the country, and animal skins and hides can be well utilised for industrial purposes and export.

Raw Materials

The Gondwana centre, which has recently come into existence on the heights of the Satpura Mountains, is exploring the possibility of developing special flower crops as well as the cultivation of drug plants and exotic plants. Great wealth can also be yielded by the oil-possessing grasses. Carefully organised and intensive botanical surveys can indicate the varied uses of the rich plant life of our forest areas.

The presence of various types of clays has practically gone unnoticed in mountain areas. Such clays are extremely valuable for developing ceramics. Rare earths are used for industrial purposes, and some earths are useful for local building purposes. Unless there is a proper discovery and study of these seemingly useless natural resources,

economic development of tribal areas cannot make rapid progress.

Stone, timber and clay have been the raw materials used in the economic life of tribal people for centuries. Stones are used by plain dwellers outside the regions in which they are found, but quarries are hardly developed in mountainous regions, probably due to lack of transport and communication facilities. Though enormous stone resources are available in tribal areas, roads have been constructed at a cost of Rs 200 per mile in tribal areas, without using the available stone resources.

The proper use of trees yielding commercial timber, or the use of wild fruits, or the use of ornamental trees is hardly a planned programme of economic development. Trees which have proved of immense value to the people in decades of prosperity and want, like the *mohuva*, *achai*, *beria*, *chuonji*, wild mango, *jamun*, etc., are not receiving the attention they deserve by the village and cottage industries planners.

Developing Tribal Economy

Planners of cottage industries seem to suffer from some kind of an inferiority complex in face of the gigantic plans of industrial development of urban communities. It seems to be generally believed that cottage industries must be small, and deficiencies of management and organisation contribute to the failure of projects for their development. It is economical to take advantage of large quantities of raw materials available in a region. The manpower problem and the local skills and market must be closely studied, and then the entire local materials should primarily contribute to the development of the local tribal economy. Only the raw material for industrial

purposes should be properly marketed in major cities as well as abroad

Due to centuries of neglect and absence of fertiliser and other treatments, trees which are more than a hundred years old, are providing fruits which are hardly marketable. The rehabilitation of the flora on the mountains and in forest regions can bring much wealth to the tribals.

Industrial Development

The development of industries in a tribal area must be based on four factors: (a) the availability of raw materials, (b) the needs of the consumer in the producing community, (c) the requirement of the local market, and (d) the availability of surplus labour and leisure time for the people. Raw materials are available but they are only used for producing a few marketable commodities. The tribals are only aware of the local weekly market, and sometimes they take advantage of a nearby town market. As stated previously, they are unaware of the availability and the possible use of raw material and natural resources outside their area. They lack initiative, business capacity and production know-how to take the maximum advantage that Nature offers for the development of their local economies.

Their home lives are normally simple and very often self-sufficient. The standard of life as well as the philosophy of living in Nature keeps them contented and seemingly lethargic. Their food habits, clothing, shelter and the few luxuries they need to enjoy life have till now failed to provide a scope for the development of village industries. In the project area where the Gondwana Centre has obtained considerable experience amongst the Gonds in Madhya Pradesh, there are hardly a dozen skilled carpenters, masons, blacksmiths, potters

and basket-workers in a five hundred square mile area.

A slow and gradual improvement is taking place as a result of acculturation, the improvement of prices and the rise in wages as well as the scope for employment. But the community development authorities beyond providing some training of poor quality, are unable to organise the artisans or build up a market for them in the nearby towns.

Lack of Markets

The existing markets in tribal areas are seasonal, unstable and unsettled. They are held to supply the needs of the people, but the shopkeepers and small businessmen are entirely unaware of the larger markets that exist in industrial areas. The absence of an organised market, adequate, easy and cheap means of transport, and dependence almost entirely on non-tribals for marketing their local produce have upto now impeded the development of tribal economies.

The manpower problem is very complicated in tribal areas. On the whole the population is small, the size of the village community is very small, and the size of the agricultural holding is also small. The forest and community development authorities provide irregular scope for employment throughout the year, and, therefore, people are unable to settle down to regular work in a village industry.

Unfavourable Climate

Women work much more than men in tribal areas. The man spends a good deal of his time on his feet, walking miles to distant places, and he is not habituated to use his hands or time in a steady manner.

He lacks the will to work. He even cannot work regularly throughout the year due to climatic conditions. During the monsoon more than 60 per cent of the hamlets are practically marooned, and there is practically no communication with even neighbouring villages. There is a shortage of labour at sowing and harvesting time. Winter days, when more work can be done, are cold and short, and, therefore, there is inadequate leisure time. Leisure is available mainly in summer from March to the end of May, and that is a time for Holi with long days of celebrations and dancing followed by the marriage season, pilgrimages and more festivals. This is then followed by days spent on repairing roofs and walls in preparation for the monsoon. And then the fields are prepared for sowing.

Traditional Skills

The tribals have developed their skills and technology over decades and centuries. These are different from the kind of skills needed by modern village industries. One of the main causes of backwardness and undeveloped village economies is the absence of leadership which knows how to divert existing skills and develop new skills required for present-day economy.

The training courses, mostly provided by the community development authorities, are not properly conceived and the programmes are not manned by persons who themselves possess the new skills and speeds required in an industrial age. The tools and implements used are of poor quality. The duration of training is very brief, and there is not enough practice to produce a good workmanship and a finished product of quality. Entirely new conceptions are need-

ed to achieve a rapid change from an old to a new economic order.

It has to be realised that the tribal economy is prosperous only if it is a mixed type of economy. The greatest scope is for forestry, even though hunting may not play a big role in the development of any sylvan economy. Tribal agriculture and animal husbandry have their own distinct place in tribal areas, and the agriculture of the plains cannot be suitable to the soil and climatic conditions of mountain areas. Tribal crafts can only find scope as a supplement to forestry, hillside millet agriculture, poultry farming, beekeeping, horticulture etc.

Contact with Towns

The problem of development of village industries in tribal areas needs long study and research and patient work over long periods amongst small, but responsive communities. The urbanites have yet to contribute their best talents without expecting high remuneration that an ill-organised and non-remunerative economy is unable to afford. The tribals have raw materials, skills and an aesthetic sense, but the contact between towns and tribal areas has yet to become more intensive and mutually beneficial for village industries to emerge and develop in tribal areas to make any significant contribution to tribal economy.

Training for Happy Life

The Gondwana centre which is created as a result of seven years' work has developed an experimental centre where experiments are carried on amongst the Gonds to develop an integrated programme of education based on the needs of a developing

tribal economy. The programmes intend to provide three-year training which can develop skills for a new agriculture for crafts like carpentry, brick-making, spinning and weaving, and prepare the youth for a career that will not destroy his adaptability to his tribal environments. Training for physical fitness, moral education and proper nourishment are part of a three year life of hard work. But theirs is a happy life where manual work is a constant factor in the classroom, the workshop and the library.

Education of the right type alone can

build a proper foundation for a progressive and enlightened tribal society capable of leadership, initiative, organised effort and a capacity for social and economic progress with others who enjoy better opportunities and who have already developed the art of modern living. Measures are needed to bridge the gaps between the village and the town, and the forest and the plain, between levels of mental and emotional developments, and between standards of living.

Bombay
14 July 1963

One of the major results of the capitalist mode of production is that, on the one hand, it transforms agriculture from a mere empirical and mechanical self-perpetuating process employed by the least developed part of society into the conscious scientific application of agronomy, in so far as this is at all feasible under conditions of private property, that it divorces landed property from the relations of dominion and servitude, on the one hand, and on the other totally separates land as an instrument of production from landed property and landowner— for whom the land merely represents a certain money assessment which he collects by virtue of his monopoly from the industrial capitalist, the capitalist farmer, it dissolves the connection between landownership and the land so thoroughly that the landowner may spend his whole life in Constantinople, while his estates lie in Scotland. Landed property thus receives its purely economic form by discarding all its former political and social embellishments and associations, in brief all those traditional accessories, which are denounced, as we shall see later, as useless and absurd superfluities by the industrial capitalists themselves as well as their theoretical spokesmen, in the heat of their struggle with landed property. The rationalizing of agriculture, on the one hand, which makes it for the first time capable of operating on a social scale, and the reduction ad absurdum of property in land, on the other, are the great achievements of the capitalist mode of production. Like all of its other historical advances, it also attained these by first completely impoverishing the direct producers.

Karl Marx *Capital*, Volume III

AGRICULTURAL RESEARCH AND RURAL ECONOMY

A R KHAN

Agricultural research has an important role to play in the improvement of farming. The Government's interest in technological development is evident from the chain of research institutes established by it all over the country. Though the results of their work are of great practical value, they have not made much impact on the rural economy due to the peculiar social and economic conditions in the rural areas.

ALTHOUGH agriculture is the largest occupation in India engaging about 70 per cent of the people and accounting for more than half of the national income, it has not been able to sustain the ever-increasing population of the country. The average productivity of land in India and the per capita income of the Indian farmer are, perhaps, the lowest in the world. Farming is still being carried on as a way of life rather than as a business. Technology which has made great advances amounting to a revolution during recent years has not made much impact on the rural economy.

It may be of interest to examine the part played by agricultural research to improve farming. During the last century three important contributions were made by science to farming. The first was the birth of the fertilizer industry in 1843. From the reactions which take place between fertilizer and the soil was evolved the technique of fertilizer application and placement. The second, which came after about 60 years, was the new way of producing better varieties of plants. And, the third was the harnessing of mechanical power for cultivation. Technology has since made so much advance that, if it is applied ruthlessly to the

best lands, the bulk of our rural population will be thrown out of employment and will have to be absorbed elsewhere. This will give rise to new problems of social and economic readjustment without which the gap between science and farming cannot be bridged.

Research Institutes

The importance the Government attaches to technological development in changing the face of the country may be evident from the establishment of a chain of research institutes and commodity stations all over the country. Some of the basic and applied researches carried out in these institutes have yielded results of great practical value. The Pusa wheat is reputed for its quality, resistance to plant diseases, high yield and wide adaptability to the soil and growing conditions in different parts of the country. Its popularity has rested for more than half a century on the confidence shown by the farmers and consumers alike. The indigenous thin varieties of sugar canes, giving a paltry return in the form of jaggery to the farmer, have now been replaced by the thick Coimbatore varieties yielding 50 per cent or more return. The impact of this innovation

is evident from the change in the rural economy caused by the establishment of sugarcane factories and the employment opportunities they offered to the rural population.

In respect of millets, the technique of hybridisation is being extended to jowar and bajra with a view to evolving high-yielding varieties. At a number of stations improved agronomic practices relating to millets are also under study. In the field of cotton research the acclimatization of sea-island cotton of the Andrews variety in Kerala is a significant development. Extra long staple cotton varieties have been evolved in Madras and the Punjab and recommended for commercial use. A large programme of hybrid maize seed production has been taken in hand and several improved varieties of subsidiary food crops like tapioca and potato, vegetables such as tomato and brinjal and fruits like grapes and papaya, and pulses and oilseeds have been evolved. Dosage of fertilizers for different crops and their water requirements have been worked out. Work on weed control and plant protection measures by spraying chemicals has yielded useful results.

Third Plan Programme

In the Third Plan, the Indian Council of Agricultural Research has a programme of enlarging facilities for research in the States through expansion of the existing agricultural institutes and by the setting up of experimental stations in different regions based on the soil and climatic conditions.

All these developments show that gigantic efforts are being planned to break the static nature of rural life in India. But experience has shown that high level research in agriculture alone does not lead to improvement. The level of agricultural research in India is quite high and can be favourably com-

pared with that of any advanced country in the world. But the fruits of research, unfortunately, have not made very great impact on the rural economy. The main weakness lies in the social order of the country and reforms which is a prerequisite for any improvement have not yet been completed. The smallness of holdings may not come so much in the way of raising production as their scattered nature and the crop pattern. The large holdings, having definite cropping patterns, should be operated efficiently and economically under the joint management of farmer members of the enterprise. This will erase the chessboard appearance of the village by giving it a new look of a single farm. The close association of persons growing the same crop will encourage the collective use of cooperatively owned resources and stimulate the healthy spirit of competition for better production. Some of the innovations may be taken up individually but, by and large, the bulk of them will have to be pushed through co-operatives.

The extension service has to be strengthened to raise productivity, promote intensive agriculture and expand job opportunities. It is quite unrealistic to expect an easy implementation of research results without this service. Those who have not yet given thought to the sociological and psychological aspects of the work may get easily annoyed at the slow pace at which research findings are being accepted by the farmers. This problem has also baffled the workers. The human factor appears to be mainly responsible for this state of affairs. The realisation of the importance of the human factor will open up avenues for a new line of research. This should be developed and should form part of extension research. The process of carrying the results of researches

to the consumer (the farmer) and of carrying back the problems of the consumer to the producer of research (the scientist) is the main work of extension service. This is a new area of activity through which the gulf between the laboratory and the field should be bridged.

Extension Service

It will not be out of place to mention briefly the work done so far in this regard. The establishment of the Central Institute of Community Development with the main purpose of conducting research in the problems of community development and providing training in that field was probably the first step in this direction. Recently at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, which has a long tradition of high level agricultural research, an independent division of agricultural extension was started. The division has the advantage of having the services of experts in natural sciences and social sciences like psychology and rural sociology. They are also experts in home economics and audio-visual education. The division carries out programmes of post-graduate teaching and research in agricultural extension leading to the Master's and Doctor's degrees.

The researches in agricultural extension are likely to have a great impact on the rural economy. The most effective ways of communicating the results of researches to the farmers are being developed. It has been found that demonstrations are very effective in convincing the farmers of the value of new research findings. The psychological and sociological factors causing resistance to changes are being studied. It has been

found that certain innovations are better accepted by farmers with high socio-economic status than by the average cultivator. Efforts are also being made to find out other important factors influencing the farmers' attitudes and prejudices, values and beliefs, levels of aspiration and expectations, receptiveness to changes and motivation. Researches are being planned in the field of decision-making by farmers.

Leaders' Role

Attention is being focussed on the role of leaders in accepting the recommendations on the scientists' findings. It has been found that the leaders who influence opinion in the villages, can be important from the point of view of implementation of new and improved practices in agriculture, thereby improving the rural economy. Several studies are being planned in the adoption of new practices which are expected to fill the gap between research and practice.

There is no doubt that outstanding researches in the field of agriculture have been made in India. These could have made a great impact on the rural economy of the country. But the impact has not been as great as one would have wished it to be. There is a great need for coordinating and synthesizing these researches. The researches in the long run should improve agriculture in the country. This is the validity of research. It is being provided by 'extension' which is trying to synthesize different researches at the common focus, the farmer who must improve his lot to contribute to the development of the rural economy.

New Delhi
5 August 1963

OUR BONE RESOURCES

S K BARAT

The Committee on Utilisation of Food and Agricultural Wastes appointed by the Government of India estimated the annual availability of raw bones in India at 3.6 lakh tons approximately, valued at around Rs. 7 crores. Only 38 per cent of these are collected and processed. Intensive salvaging of bones is hence necessary. The committee has recommended that every effort should be made to export as much of bone products including bone-meal as possible.

INDIA is pre-eminently rich in bone resources with a very considerable potentiality for further development. It is generally estimated that one-fourth of the body weight of cattle consists of bones. Taking the average body weight of Indian cattle at about 400 pounds and reckoning the casualty rate among them at a conservative estimate of 8 per cent, it would appear that 24.6 million carcasses of bovine animals should be theoretically available every year, accounting for 10.9 lakh tons of bone from this source alone. However, the actual availability is very much less. Bones of

larger animals mostly from the fallen stock are commercially collected since only a small portion of these animals enters the slaughter house. The Committee on the Utilisation of Food and Agricultural Wastes appointed by the Government of India recently estimated the annual availability of raw bones in India at 3.6 lakh tons approximately valued around Rs. 7 crores. The break-up figures for the different species of animals are given in the table.

Of these at the moment only 1.36 lakh tons of bones, that is about 38 per cent of the estimated availability of the same are

RAW BONES FROM DIFFERENT SPECIES OF ANIMALS

(In lakh tons)

Species	Dead	Slaughtered	Total
Cattle	2.495	0.097	2.592
Buffalo	0.952	0.068	1.020
Horses & ponies	0.013		0.013
Camels	0.017		0.017
Total	3.477	0.165	3.642

actually collected and worked upon within the country by the 98 bone crushing units, the rest going waste for want of any organised effort. Intensive salvaging of the bones particularly from forests of Uttar Pradesh, Orissa and Assam should be undertaken since considerable quantity of bones of cattle and wild animals remains abandoned in these states. The supply of bones in our country is rather inelastic, these being mostly derived from the dead animals.

Difficulties of Collection

Collection of bones however constitutes the main difficulty since our livestock is scattered all throughout the country in its 55 lakh villages. There are in fact numerous small villages with an average cattle population of only 350. Reckoning the mortality rate of our cattle at about 8 per cent the annual availability of carcass in such villages works out to be less than 30 per village. It would, therefore, seem evident that with such casual supply of carcass in the villages, it would be rather difficult to organise effective collection of the bones at the village level. However, such work can be advantageously organised with the existing machinery in the rural areas, viz., village panchayats, community projects administration, rural flaying centres, etc. The animals dying in the countryside should be dressed in the nearest flaying centres. All dead animals in the villages should be disposed of at a fixed place.

Purchasing depots in the block development areas could perhaps be set up where the bones collected from the neighbourhood could be sold against cash at a reasonable rate sufficiently attractive to the primary collector. Greater collection would

be possible only if the incentive of a higher price is offered to the primary collector. A system of incentive guaranteeing adequate return to the primary collector should be worked out to boost up collection. In most cases, such collection does not work out to be a profitable proposition because of the high rates of freight and transport involved.

Bones constitute a valuable source of phosphatic manure. Super phosphate with its P_2O_5 content available in water soluble form is more suitable for use as a phosphatic fertiliser in most of the soils in India. Commercial sulphuric acid if available cheaply in the vicinity of the bone producing area could be advantageously used in converting the bones into super-phosphate at least for local use. However, in many parts of the country, bone fertiliser is not readily accepted mainly on religious grounds although its relatively high cost also to a certain extent stands in the way of its more general use. Attempts are now being made particularly in the South to popularise the use of bone fertiliser by offering subsidies, etc. The Government of India and State Governments pay a subsidy of 25 per cent of the retail value when bone meal is distributed by the latter, bone meal being more popular as an ingredient in readymade fertiliser. It is however desirable that such bone meal is adequately sterilized particularly against anthrax. Mineral phosphates can also be used conveniently in places where super-phosphate is not necessary.

Foreign Exchange Earner

In view of the lack of any mineral phosphate resources within the country many voices have been raised in recent years

against the free export of bone or bone products rich in P_2O_5 . It is urged that these should be retained for meeting the internal demand for phosphatic fertilizer within the country. However on final analysis of the current international price of the exported bone or imported phosphate rock reckoned per unit of P_2O_5 , contained it would seem that the price per unit of P_2O_5 is more competitive in case of super-phosphate. In fact for each ton of P_2O_5 exported in the form of bones or bone products, a little over three times as much of P_2O_5 in equivalent quantity of phosphate rock can be imported. At the present international price level for bones and bone products it is therefore worthwhile for India to export as much of these as possible, its own internal demand for phosphatic manure being met through import of phosphatic rocks which are readily available abroad. In the context of the above facts, it has been officially recommended by the Committee set up by Government of India that so long as supplies of phosphate rock are readily available to us from abroad and the main use of bone products within the country is as manure, every effort should be made to export as much of bone products including bone meal as possible. Out of the foreign exchange thus earned, a portion may be utilized to import mineral phosphates such as phosphate rock or hyper phosphate for replenishing the P_2O_5 lost through the export of bones and bone products.

The bone industry in our country is already export-orientated to a considerable extent inasmuch as 74 thousand tons of bones and bone products on an average are annually exported to United Kingdom, Belgium, United States of America, etc., earning about Rs 25 crores. Besides, India produces approximately 32 to 35

thousand tons of bone meal every year. But the export of this item is at present banned. If this restriction is removed, the foreign exchange earning capacity of the industry will be greatly increased. This will ultimately mean a better return to the primary producer which will in turn encourage greater collection of bones from the available sources.

Decalcification

The other possible alternative utilization of bones will be to convert them into ossein and then into gelatine if necessary. Bone may be considered as a collagenous matrix filled out with a micro crystalline inorganic phase of approximate composition of calcium phosphate but containing other ions also. As such when bones are treated with dilute hydrochloric acid at room temperature ossein and a solution of calcium phosphate in dilute hydrochloric acid are mainly obtained. It has been experimentally observed that approximately 14 per cent of the acid is necessary to effect complete decalcification of the bone calcium phosphate being recovered on neutralizing the acid with lime water or sodium hydroxide. In this process calcium chloride and sodium chloride are also produced and are conveniently removed by washing with water. Through careful adjustment of the pH and removal of the chlorides, it is possible to obtain di-calcium phosphate in a reasonably pure form.

New Outlet

At the moment, the internal consumption of gelatine is rather limited and a considerable portion of the installed capacity for its manufacture is lying idle. The export trade potentiality of ossein and technical gelatine

will therefore have to be explored and if any reasonable demand for these products exists necessary steps will have to be taken within the country to process some of the available bones into ossein and gelatine. Of late Japan has been interested in importing a large quantity of ossein and with our comparatively cheap labour, we should be able to compete in this field. Moreover,

conversion of bone to ossein will give a new outlet for chlorine utilisation, and would eliminate much of the bulk freight charges, in addition to obtaining dicalcium phosphate and residual liquor as by-products which besides being used as valuable fertilizers have many other industrial applications.

Madas
19 April 1963

Some people might think that if the value of a commodity is determined by the quantity of labour spent on it, the more idle and unskilful the labourer, the more valuable would his commodity be, because more time would be required in its production. The labour, however, that forms the substance of value, is homogeneous human labour, expenditure of one uniform labour-power. The total labour-power of society, which is embodied in the sum total of the values of all commodities produced by that society, counts here as one homogeneous mass of human labour-power, composed though it be of innumerable individual units. Each of these units is the same as any other, so far as it has the character of the average labour-power of society, and takes effect as such, that is, so far as it requires for producing a commodity, no more time than is needed on an average, no more than is socially necessary. The labour-time socially necessary is that required to produce an article under the normal conditions of production, and with the average degree of skill and intensity prevalent at the time. The introduction of power-looms into England probably reduced by one-half the labour required to weave a given quantity of yarn into cloth. The handloom weavers, as a matter of fact, continued to require the same time as before, but for all that, the product of one hour of their labour represented after the change only half an hour's social labour, and consequently fell to one-half its former value.

Karl Marx *Capital*, Volume I

RURAL EMPLOYMENT AND THE PLAN

CHITAPRIYA MUKHERJEE

If we wish to establish a self-reliant and self-contained village community it is necessary to ensure a balanced relationship between the organised private sector of non-agricultural industries and the villages, between mechanized and labour-intensive industries and between the town-oriented industrial economy in general and the village-oriented decentralized economy

THE prospects of our Third Plan closing with an even higher figure of unemployed and underemployed¹ than that at the end of the Second Plan seem to baffle many of us, have we not, through a two-decade period of sacrifices and strain, paved the way for a society where unemployment, and its allied problem of unequal distribution of income, would be absent? Is something seriously wrong with the Plan itself or its implementation?

Divergence of Interests

Of the manifold problems—ranging from a sudden spurt in population growth outstripping the productive capacity of the soil to the failure of domestic savings to keep pace with the desired rate of investment—that confront this country, which was battered to exhaustion as a result of a long period of economic exploitation ending with a

fruitless global war and Partition thrust on us, the lack of opportunities to utilise fully the human capital is undoubtedly the foremost. Suffering from a strange and incompatible combination of the Old and the New, of the organised monopolistic growth in the inflated towns and cities and utterly disorganised and scattered agricultural sector, our Society—already having both in its social and economic fabrics an ingrained sense of individualism and class distinctions in some form or other—carried the legacy of a wide divergence of interests and outlook between the poor and the rich, rural folk and the urbanites, educated and the uneducated, white collars and intellectuals and the manual workers.

Solutions prescribed by countries now placed in a better and stronger position but many of which, incidentally, can think

1 "In the course of the Second Plan the additional employment opportunities created amounted to about 8 million, of which about 6.5 million were outside agriculture. The back-log of unemployment at the end of the Second Plan is reckoned at 9 million." "In addition, underemployment in the sense of those who have some work but are willing to take up additional work

cannot be precisely estimated, but is believed to be of the order of 15-18 million." "during the Third Plan, the addition to the labour force may be of the order of 17 million." "it is reckoned that the Third Plan may provide additional non-agricultural employment of the order of 10.5 million and additional employment in agriculture of about 3.5 million—*Third Five Year Plan*, Pp 156, 159

of solving their own unemployment problem only in times of war², hardly seem to fathom the real problem that moves in a vicious circle in our country suffering from a surfeit of manpower bogged down to the subsistence level, consequent absence of savings and a conflict of aim between higher productivity and employment. We have embarked on our difficult enterprise at a time when there is no scope, as in the case of the pioneer Westerners, to squeeze out its 'surplus' population to vacant continents abroad, nor are there colonies to exploit and control or empires to rule³.

When Malthus is discarded and the whole world eagerly joins the 'freedom from hunger' campaign, almost all 'underdeveloped' countries simultaneously launch their plans of national self-sufficiency, and the world trade takes a course that would eventually leave us with hardly sufficient exportable products to be exchanged with others on the basis of the old theory of "comparative

cost". Whatever the definition or the purpose of foreign "aids" may be⁴, stronger nations rendering help to the underdeveloped countries, cluster round associations of their own practically in disregard of the efforts in the other direction by the world organizations, and thereby bring down the prices of products which underdeveloped countries had exported earlier. In spite, however, of all adversities over which we can exercise no control, it has to be admitted that we have achieved some tangible results, and the proportion of working to total population in our country has definitely taken an upward swing since 1951⁵.

Approach to Planning

Faced with the formidable task of handling all problems at a time and being committed to attaining results which countries now more advanced took much longer to achieve under more favourable conditions, we have been pursuing a technique of plan-

2 "There are those who would deny the possibility of technological unemployment. The reasoning on which they base their argument is enough so far as it goes. But it does not go far enough. Unemployment in the United States was under control until World War II, when it rose up to abnormal size. If the most prosperous nation of the world cannot keep its labour employed when birth control is keeping the labour force down by millions, perhaps tens of millions, what would the volume of unemployment be if the negative phase of the mechanical revolution had never occurred?"—E. W. Zimmermann, *World Resources and Industries*, p. 110.

3 China with her set of problems and potentialities largely resembling those of our country, is committed to a pattern of growth which does not fit in with our concepts of development. Japan, with her dazzling success at the turn of this century, is now busy making a fresh assessment of her resources after she has been shorn of her outstretched empire and has been saddled with a much larger population than what she had earlier. "The spectacular drop in birth-rate in recent years in Japan (7 per thousand), due to a realization on a national scale that the country has reached the maximum population it can support, should convince one that what has been done in Japan may be repeated in India."—*Report of the Commission*

for *Legislation on Town and Country Planning*, p. 41.

4 "The term 'aid' is often loosely employed to include any investment or credit such as, for example, is extended in support of medium-term exports of machinery and equipment to developing countries. Besides, part of the aid at present available to developing countries, particularly from some European countries, is for such short periods and on such high rates of interest that it appears scarcely distinguishable from ordinary commercial credit."—Dr. B. K. Madan, Executive Director, Reserve Bank of India, on April 30, 1963, in *Reserve Bank of India Bulletin*, May 1963, p. 609.

5 *Census of India 1961* (paper No. 1 of 1962) pp. 403 and 409, and statements 15 and 16, pp. XXII and XXIII. Index of increase in population, with 1951 taken as base (100), stood at 121.69 in 1961, index of increase of workers stood at 133.81 in 1961. The index in 1951 as 100, population index stood at 150.70 in 1951 and at 183.40 in 1961, percentage of total workers during the period rose from 126.50 to 169.14. Percentage of workers to total population was 46.61 in 1951, 39.10 in 1951 and 42.98 in 1961. Effect of Plan outlays on the employment growth is evident, of the total outlay in the public sector in the two plans (Rs. 6,560 crores) agricultural programmes

ning which is in a sense unique and is more difficult to implement. If it is slower than some other methods, it is at the same time less painful in its process of implementation and has the possibility of far better results as soon as we cross the hump—the 'take off' stage—and enter the stage of 'self-sustained' growth. In the spate of controversies that centre round fixation of priorities, some advocate foremost consideration to equitable distribution of whatever wealth we have got and to the question of employment to all, others argue that equitable distribution may come later and it, in the process of generation of more wealth or rather of the base for creation of wealth at an accelerated rate in the near future, some widening of the gap in existing income-differences takes place, we need not feel pessimistic about the ultimate results. With improvements in techniques of production, as the argument goes, some initial unemployment or displacement of labour has, in different periods of history, taken place in every country, but only to be followed by wider diffusion of the means of production and of employment. The changes we are now going through should not, it is suggested, be measured just in the quantitative terms of a few additional avenues of employment, or of some unemployment, but be measured

in the qualitative terms of changed, reoriented approach to the way of life that had so long created a vicious spiral of unemployment, poverty and inadequate means of generating wealth.

Achievements

• Steering through these competing claims of productivity, employment and equitable distribution of wealth, the planners have been able to create, during the decade of the two plans, a strong base of reproducible tangible wealth⁶, provide employment or gainful occupations for about 50 million people since 1951 and make adequate provision for proportionately an even higher rate of employment in the Third Plan⁷. Although the inevitable trend towards concentration of wealth in fewer hands continues⁸, various fiscal, monetary and administrative measures are gradually being evolved and adopted simultaneously to siphon off the extra purchasing power placed in the hands of those who have, in the process of the implementation of the Plan, replaced foreign manufacturers, and also other beneficiaries of the developmental expenditure.

Technology and Employment

While experts agree that the problem in our country is basically one of underem-

in general covered Rs 1,331 crores or about 20.3 per cent expenditure on mining, and industries covered 26.9 per cent, that on construction accounted for 6.3 per cent, transport storage etc covered 28.4 per cent. Social services and others covered 18.1 per cent. Comparing this with the index of increase in different categories of workers, we find that with 1951 taken as base (100), percentage increase of cultivators was 40.86, that of agricultural workers 14.21, workers in plantations, forests, etc increased by 25 per cent, workers at household and in manufacturing industries increased by 57.97 per cent, those in construction by 39.04 per cent, in trade and commerce by 3.87 per cent, transport, storage, communications by 39.75 per cent, and residuary workers in services by 32.35 per cent.

6 Reproducible tangible wealth increased from Rs 17,086 crores in 1949-50 to Rs 32,164 crores in 1960-61, and total tangible wealth was estimated to be Rs 34,940 crores and Rs 52,405 crores respectively during the said period—*Reserve Bank of India Bulletin*, January 1963.

7 According to the estimate made by the Registrar-General and the Central Statistical Organisation in 1961, population is likely to be 492 million in 1966, 555 million in 1971 and 625 million in 1976, increase in labour force over this period may be the order of 70 million. This consists roughly of about 17 million in the Third Plan, about 23 million in the Fourth and about 30 million in the Fifth Plan—*Third Five Year Plan*, Pt 156, 750.

8 Vide *Reserve Bank of India Bulletin*, September 1962.

ployment in the rural sector, opinions invariably differ on the methods of utilisation of this force 'Relief' employment as such is not denounced⁹ but as subsequent experiences had perhaps shown, it hardly adds to the total wealth or productivity of the country, to resort to this kind of employment with the expectation that this, when magnified, would by its sheer volume, perform what 'productive' employment on a smaller scale could achieve, hardly finds support from those who look beyond the immediate and firmly believe that denial of better techniques for attaining higher productivity per worker, cuts at the very root of 'progress' Anticipating the argument that advanced countries with better techniques of production have not so far been able to eradicate unemployment in peace time, it is emphatically argued that if those countries have failed, it is not so much because of the technical achievements towards increasing productivity of labour, as due to the failure of human institutions and attitudes, which guide and are entrusted with the task of utilising the Machine and the Man¹⁰

Official view-point¹¹ fully endorses the theory and, barring some inevitable admini-

nistrative sluggishness admitted by the Planning Commission itself—lays great emphasis on import and manufacture of machineries, particularly for the industries which should be capital-intensive and produce at a rate that would not only meet the increased domestic demand but would leave enough for export As the records of the last decade show, import of machineries of various kinds has far exceeded other imports and much of the present foreign exchange crisis is explained by this item which no doubt creates a strong base for increase of productivity in future¹²

Variety of Industries

At the same time, however, the Planning Commission takes into consideration the capacity of different categories of industries to absorb the additional manpower¹³ and simultaneously places emphasis on "agro-type" of cottage industries, "feeder" industries, "service type" of cottage industries etc and allied cottage and smallscale industries which can, it is expected, create—with suitable protection in the initial stage—sufficient volume of consumers' goods and can absorb a large number of unemployed or underemployed manpower with a small

9 Reference may in this connection be made to the "11-point programme" for expanding employment opportunities announced by the Planning Commission in 1953. Proposal for adoption of 'unorthodox' methods for creating *productive* employment has been criticised by many economists as being equivalent to unemployment doles. See "Unemployment and Unorthodox Methods" by Bhabatosh Datta in *Essays in Plan Economics*

10 "What stands in the way is not a machine age, but the survival of a pecuniary age. The worker is tied helplessly to the machine and our institutions and customs are invaded and eroded by the machine, only because the machine is harnessed to the dollar. We cling to old creeds and we profess ideas and sentiments that have no real hold on our living activities, because a regime of pecuniary profit and loss still commands our allegiance"—John Dewey *The House Divided Against Itself*

11 Referring to the problem of unemployment and to the three approaches towards its solution viz, *spreading out of employment opportunities, rural electrification and industrialization and organizing rural works programme for increasing employment through small industries* the Planning Commission observes, "Even though in the first instance, the introduction of new production techniques may result in a decrease in employment, it is expected that there will be significant long term benefits in revitalising the rural economy"—*Third Five Year Plan*, P. 161

12 During the years 1958-59 and 1961-62 we imported machinery and transport equipment of all categories to the extent of about Rs 1,200 crores out of total imports of approximately Rs 4,000 crores

13 In estimating the additional non-agricultural employment during the Third Plan—(105.30 lakhs in the aggregate of which 67.50

amount of capital per worker. Encouragement to traditional or ambar charkha, handloom etc., and evolving a 'common production programme' with the organised sector, are evidence of such measures taken during the last decade and proposed to be intensified in the Third and subsequent Plan periods.

Problem of Rural Unemployment

The magnitude and nature of the problem of rural unemployment being what it is, measures taken so far or scheduled to be taken would not wipe off the unfortunate wastage. Assuming that the secular trend of population growth would be affected only in its fringes by the positive measures for

family planning, the problem will remain one of *deciding now on priorities* with regard to utilization of capital equipment and manpower for such items of production which—unlike some specific heavy and basic industries or even such consumers' goods¹⁴ for which we propose to create an export market—remain, so to say, on the borderland in so far as the technique of production is concerned. While the general proposition that productivity of labour has to be increased on all fronts is incontrovertible, it seems we have—in view of the present level of underemployment, prospects of too high a population growth before industrialization is achieved¹⁵ and possibilities of our export trade being not too bright in

lakhs would be accounted for by direct employment and the rest in trade and commerce calculated at 56 per cent as indirect beneficiaries of developmental programme), the Planning Commission has worked out a rough employment-investment ratio for employment in *construction phase, continuing phase*, and also in respect of *indirect employment*. For employment in construction (i) *irrigation projects* show a ratio of 7,000 man-years for a crore of rupees, (ii) *power projects* a ratio of 1,600 man-years for a crore of rupees and (iii) for transport construction, particularly in railways, a ratio of 1,900 man-years. In the case of *continuing development*, widely divergent ratios naturally apply. For small-scale industries, employment of one person would mean an investment on the average of Rs 5,000, for handicrafts the estimate is Rs 1,500, for coir and sericulture it is roughly Rs 1,000. Under large and medium industries there will, again, be different norms. Capital required per person in steel industry is estimated to be Rs 1,00,000, that in fertilizers Rs 40,000, machine tools Rs 25,000, heavy machine building plant Rs 1,00,000, coal mining machinery Rs 60,000, etc.—*Third Five Year Plan* Pp 753-757. As against an overall investment of Rs 10,400 per worker in the Second Plan, the estimated investment of Rs 9,700 during the Third Plan has been stated to be an underestimate by Dr A Vaidyanathan "Increasing the Employment Potential", in *Problems in the Third Plan, A Critical Miscellany*. According to the findings of the *Techno-Economic Survey of West Bengal* development of large-scale industries during 1961-71 would absorb 73,500 persons and investment would be of the order of Rs 237.82 crores, investment per worker would thus be about Rs 32,300. Expansion of existing engi-

neering industries would require an investment of Rs 384.30 crores and employment would be available to 35,900 persons, investment per worker comes to about Rs 1,07,000. New small-scale industries would absorb 6,400 persons and investment would be of Rs 41.69 crores, investment per worker comes to about Rs 65,000. On the aggregate, in order to absorb 1,15,800 workers the total capital outlay would be for Rs 663.81 crores, investment per worker comes to Rs 57,000. Also refer to *A Design for Development of Village Industries in West Bengal* by Nistaran Chakravarty ex-Director State Statistical Bureau, West Bengal, Para 19 1-19 5.

14 With changing times we are surely coming out of that '*damned wantlessness*' about which Western salesmen had accused the oriental people. Conscious though we are that 'wants are artificially created' and that modern entrepreneurs are 'the creators of new wants', we are now keen on having as soon as our funds permit, to possess such items of products which were once considered as luxuries. And this surely creates the field for wider economic activity.

15 In 1800 A.D. estimated world population was 905.6 millions, Europe had 187 millions, North America 5.7 millions, Central and South America 18.9 millions, Africa 90 millions and Asia 602 millions. In 1936 the corresponding figures were (world population being 2,115.8 millions) 533 millions, 140.3 millions, 127.5 millions, 151.2 millions and 1,153.3 millions. It is estimated that while the population of Europe and North America will remain more or less static by 2000 A.D., that of Africa will be 250 million and of Asia, 1,900 million.

" as industrialization of a young country advances and the ratio of farm to non-farm popu-

the context of developments elsewhere—to make up our mind about the *sphere where mechanization and capital-intensive technique would be absolutely essential* and where it should be scrupulously avoided

Increasing Productivity of Land

In the agricultural sector, for instance, if we have to choose between higher productivity of land with a given amount of labour and better application of science—which surely is not synonymous with mechanization—on the one hand, and same level of land productivity with some labour saving mechanical devices on the other, our preference under the given circumstances will, possibly, be for the former although we might quite agree on the point that as in the U S A, U S S R or other European countries, a combination of both mechanization (as distinguished from use of tools with animal power and not inanimate power) and better application of science would yield not only sufficient food for us and our posterity, but would, at some distant future, leave sufficient surplus for export and at the same time would release a larger number of people for non-agricultural work. As we rule out tractors, harvesters, etc., on grounds of cost and labour

displacement far outweighing the long-term advantages and prefer to stick to the good old plough and bullock, with better seeds, fertilizers, water, cooperative farming, better land tenure system, enlargement of the size of holdings and all that, it seems we accept thereby the inescapable proposition that the problem is *not so much the saving of labour as of increasing output on a given plot of land*

Problem of Mechanization

While most of the tillers of the soil of our country, engaged for long, arduous hours in back-breaking labour for a brief spell of time during the monsoon, should undoubtedly deserve, in the peak season, much needed leisure¹⁶, one would agree that their cause (or for that matter, of the whole country) would be better served, if they are relieved from their forced idleness during the remaining months of the year. Leisure during peak months is, no doubt, necessary, but if that means, on the one hand, drainage of foreign exchange both for the tractor or the harvester and for the fuel oil, and on the other hand, creation of unemployment amongst the agricultural workers we are led to the conclusion that we cannot simply afford to have it, notwithstanding the the-

lation declines, a point may be reached in the economic development when even *high per-man productivity* no longer suffices to yield exportable surplus"—*World Resources and Industries*, P 158

16 In 1850 the average American worked seventy hours a week, today he works fortythree. In 1850, an American cultivator used animal power to the extent of only 1.8 horse power, in 1940 power used per agricultural worker was 27.8 horse power of which mechanical power constituted 26.3 horse power and animal power only 1.5 horse power. Per capita daily output of energy in horse power hours in 1939 was 12.27 in U S A, 15.74 in Canada, 0.46 in China and 0.49 in India. A 'mobilised' farmer can do in 24 hours as much cultivating as a farmer unsupported by horse power can do in 10 days. "Labour saving devices thrive most where labour is scarce."

In general it may be said that *mechanization* is most suitable to regions of abundant land while the *direct application of science* to agriculture seems more suitable to regions where land is relatively scarce. Mechanical labour-saving devices replace manpower and permit the cultivation of larger areas per man. They thus raise *per-man productivity*. Science tends to raise the *productivity per acre, per plant per animal*. It tends to intensify agriculture whereas machines favour expansion over wider areas. In countries of high *per-acre productivity* greater expenditure of labour may compensate in part for the reduced use of land"—*World Resources and Industries*, P 158. Also refer to "Economic Basis of Land Reform in Underdeveloped Countries" by E. J. Long in the supplement *View-points on Economic Aid*, the *American Review*, July 1963.

oretical possibility of having even exportable surplus by introduction of power-driven instruments, we have to reject it as impracticable

Applying this argument to the production of such items of non-agricultural sector, in which mechanization does not add to the total output or does not require further output than what our domestic demand can absorb, but only 'saves' labour, we have to decide on how far should we suffer *unimproved loss* by way of depletion of foreign exchange and creation of additional unemployment. The fact that England or other European countries had similar transitional unemployment in the earlier part of the nineteenth century¹⁷ hardly seems to have relevance to our present conditions.

On this score, however, it seems that there is some lack of clarity in the policy followed so far in spite of all our efforts made during the last decade in respect of the problems of the agricultural and rural sector, our attention, for understandable reasons, is directed towards big industries and this largely resembles the pattern of growth

through which the western countries had passed¹⁸

Competing Industries

Assuming that electricity is the cure-all for rural industrialization, we must ensure that this new aid to decentralised industrialization goes exclusively for creation of new wealth and *not* for replacement of industries which, with a larger labour content, were engaged in fulfilling certain requirements of the society. It is true that it is difficult to draw a correct line of demarcation between new industries and those industries which were engaged so long in a cruder form of production, either with a different material or with the same material. Just as invention of petroleum in the USA created widespread unemployment amongst British coal miners or synthetic dye-stuff in Germany wiped out the Indigo cultivation from India, so will electricity-driven saw mill replace the village artisan with his long, bulky and crude saw, polythene or aluminium will replace the pottery or bell metal products made in the villages, toy makers of the countryside will lose ground to the plastic industry, and steel sheets will

17 Vide *Rural Depopulation in England and Wales 1851-1951* John Saville (chapter one The Historical Background) "the problems which the American inventor was facing during the nineteenth century were mainly problems of labour scarcity excess of space, and, as a result, scarcity of time"; "despite all this progress, agriculture throughout the Western World for most of the twenty years between the two World Wars was in dire distress, being kept alive by artificial respiration as it were"—*World Resources and Industries*, P. 163

18 "The agrarian problem undoubtedly lies at the centre of all things in the life of India today. Without a great increase—and a better distribution—of rural income, industry cannot develop to the full, since agrarian poverty severely restricts the effective demand of the numerically huge internal market, and continually maintains, or indeed

augments, the immense pool of landless or underemployed rural labour and thus keeps the workers wage low, his living conditions often unspeakably bad, and his efficiency as a natural consequence very poor. To the makers of this revolution (in India), the urban middle classes and the new business magnates or petty chiefs it is the mills, the factories, the power houses, which fill the stage and nourish national pride. This is legitimate enough, provided it does not obscure the all important fact that it is in the fields that India's destiny finally lies, and provided also that industrial advance is itself integrated and balanced which at present it conspicuously is not. Its extreme unevenness of development is inherent partly in the natural endowment, but more largely in social history"—O. H. K. Spate *India and Pakistan*

dislodge the village blacksmiths, so will the automobile displace a large number of bullock carts

But when one finds that handpounding of rice or crushing of mustard oil (or such other "agro-type" industries which were engaged, *not* in the creation of *additional* wealth but only in processing of a given amount of products) have, in course of the last few years been replaced, inspite of recommendations to the contrary¹⁹ by diesel or electrically-driven machines (small-scale industries of course), one has only to scan the employment figures for female workers at least in a large part of the country²⁰ and enquire if social conditions have so changed during the last decade as to warrant withdrawal of a large section of the female workers from a field of economic activity previously controlled by them, and their dependence on the earnings of the male folk only. If it is assumed that "in the first instance, the introduction of new production techniques may result in a decrease in employment, it is expected that there will

be significant long-term benefits in revitalising the rural economy" (*Third Five Year Plan*, p 161), it may reasonably be asked what occupation in the non-agricultural sector would be available later if the traditional industries continue to become more mechanised²¹

Benefits for a Few

It is true that a section of the agricultural population—the section which owns sufficient land to yield substantial 'marketable surplus'—has in recent years derived cash benefit from higher price of agricultural products. But, in the absence of a definite and determined effort at utilising that income for encouragement of such industries in which all the rural people could participate, a large part of that income of the handful of agriculturists goes either towards acquisition of more land (mostly as distress sale from the poorer to the richer section), or towards purchase of such fancy goods as transistors, scented oil, shampoo and other similar products, or is spent on litigation

19 The Village and Small-scale Industries (Second Five Year Plan) Committee (1955) *emphasised the avoidance of further technological unemployment* in the traditional village and small-scale industries during the process of planned development. From the *Third Five Year Plan* (p 443) it appears that inspite of certain directives given under the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958, some of the main intentions of the Act were not fulfilled by the States. Also refer in this connection to page 520 of the *West Bengal Census 1951* (Volume VI, Part I-A Report), and pages 154-155 of *A Design for Development of Village Industries in West Bengal* (1959). Amongst the persons engaged in West Bengal in the processing of grains and pulses in 1901, there were 12,500 males and 1,90,280 females (total 2,02,780), in 1951 there were 23,270 males and 88,140 females (total 1,11,410). As against 10,61,876 self-supporting females in 1901 in West Bengal amongst non-agricultural classes, there were only 6,09,122 in 1951. Large-scale industries absorbed only 85,457 female workers in 1951 as against 61,300 in 1901. The difference is too appreciable to be

ignored. The census of 1961 in West Bengal and also in some other States confirms the same trend.

20 Refer to statements 26 to 29 of the *Census of 1961* (pp XXIX-XXXI), paper No 1 of 1962. Inspite of a general increase in female employment—mostly in the agricultural sector—marked deterioration has set in since 1951 and accelerated in 1961 in some categories of work.

21 Incidentally, whatever inadequacies the *ambar charkha* or the traditional *charkha* may suffer from, and whatever promise the organised cotton textile industry may hold out for capture of export market, we find from a report of the Reserve Bank of India (vide its *Bulletin* of March 1962) that *foreign exchange outlays* on the industry have, in recent years, been consistently higher than *foreign exchange earnings*. But in the domestic market, mill cloth renders the growth of handloom and khadi more difficult. A closer integration of our export policy with our domestic consumption policy and of the mill sector with the cottage industry sector seems to be necessary both for avoiding wastage of foreign exchange and for a healthier growth of the handloom cloth.

While it is agreed that rural people have a right to enjoy such amenities of life which were so long within the reach of the urban people only (and unless surplus money flows out of the villages, industries cannot thrive) the present trend of trade relation between the industrial towns and agricultural villages seems to suggest that the imbalance continues and tends to move against the villages in general. If the few monied villagers can afford to spend their leisure months in whatever manner they choose, for most of the landless agriculturists and those having small plots of lands, the idle months are a deadweight and go to total waste.

Balanced Relationship

If a self-reliant, self-contained village community has to grow, then, while we think of popularising the cooperatives²² or the panchayats, we must at the same time, go, not one, but several steps forward to establish a *balanced relationship* between the organised private sector of non-agricultural industries, and the villages, between mechanized and labour-intensive industries, and finally between the town-oriented industrial economy in general and village-oriented decentralised economy. Even if we admit that the world situation is such that we can hardly think of implementing in toto the plans of Gandhiji or of Rabindranath Tagore, it has at the same time to be said that if we think in terms of putting new life into our innumerable villages, and of eradicating rural unemployment, then a

clear line of demarcation has got to be drawn between production, market and extent of mechanization of the organised large-scale producers of "non-essential" consumer goods on the one hand and those of the small-scale and cottage industries on the other.

Protection

It may be argued that in this modern era such a step would amount to putting the clock back, as we have to survive in this competitive world we must "modernise" our production technique in every sector. If we apply the argument to the modern industries now well established in our country we would come to the conclusion that the 'protection' against foreign competition granted to all such industries during their stage of infancy was not in conformity with the law of comparative cost and of superior natural advantages which is now being advocated. (History of steel industry in most of the European countries indicates that many countries adopted protective measures to establish steel plants inspite of absence of comparative advantage.) Our sugar industry, automobile industry or for that matter many other industries could not have survived competition had these not been granted protection. (On the other hand, Lancashire could not survive inspite of initial advantages.) And if protection holds good in such cases, why should not our small-scale and cottage industries, after those have been provided with better implements, be given protection if those are

²² Rural Credit Follow-up Surveys show the intensity of the influence of urban traders and money-lenders on the cooperatives and on the vil-

large economy in general—vide *Reserve Bank of India Bulletin*, November 1962.

found to fill up a definite void in our economy?

Purposeful Policy Needed

One of the objectives of our Plans is to find a solution to the problem of unemployment and underemployment, and we are committed to restoration of self-sufficiency (so far as it fits in with present-day conditions) in our innumerable villages. Large-scale industries have, by the very nature of their growth, failed to provide employment to all, and even if we assume that our export market will expand to such an extent as to provide employment on a larger scale (national self-sufficiency drive

in every country will not give us such an opportunity), we cannot hope to solve the unemployment problem by allowing the traditional cottage industries to wither away. A balance has to be struck between productivity and employment, the policy followed so far is to some extent indecisive and self-defeating. In the absence of a more positive and purposeful policy, village co-operatives which we are committed to establish and which we consider as the core of village life would hardly have the breathing time to grow, and the problem of rural underemployment will also continue to remain as a scar on our economy.

Calcutta
26 July 1963

Just as capital has the tendency to reduce the direct employment of living labour to no more than the necessary labour, and always to cut down the labour required to produce a commodity by exploiting the social productiveness of labour and thus to save a maximum of directly applied living labour, so it has also the tendency to employ this labour, reduced to a minimum, under the most economical conditions, i.e. to reduce to its minimum the value of the employed constant capital. If it is the necessary labour-time which determines the value of commodities, instead of all the labour-time contained in them, so it is the capital which realizes this determination and, at the same time, continually reduces the labour-time socially necessary to produce a given commodity. The price of the commodity is thereby lowered to its minimum since every portion of the labour required for its production is reduced to its minimum.

Karl Marx *Capital*, Volume III

ROLE OF SCIENTISTS AND ENGINEERS IN RURAL INDUSTRIALIZATION

M. S. ADISHIVARI RAO

The two sets of problems confronting rural industries in the context of modern scientific and technological advance are those relating to the economic objective of raising the industrial productivity and the social objective of utilizing manpower resources. The question is whether the decentralised pattern can be established as a dynamic industrial reality for which planned exploitation of modern technological developments is needed. This can be brought about by systematic research. Scientists and engineers have a very vital role to play in this respect.

RURAL industrialization is a project of large magnitude in our economic plans and presents complex problems of application of scientific and technological advances to economic and social welfare. Yet fewer industrial scientists including engineers have been mobilised in the rural sector of industries than in the urban and other sectors during periods of the First and the Second Five Year Plans. What are the reasons for this wide disparity? What are the functions of scientists and engineers in the development of the rural industrial sector? How can scientific and technical manpower be mobilised effectively in programmes for rural industrialization? These and related questions, for which as yet no agreed answers have been found should be discussed in the context of the long-range problems of rural industrialization in our developing economy in the perspective of modern scientific and technological advances.

Long-Range Problems

Unlike industries in other sectors, rural industries present two different long-range

problems of development in the context of modern scientific and technological advances for industrial production. The first set of problems is common to industries in all sectors and is concerned with progressive raising of productivity of industrial operations and processes to ensure economic survival and progress. These are primarily the problems of individual industrial units or of rural producers. They have only one solution in the modern context and that is to adopt suitable modern technological developments. They may be called problems of industrial productivity. However, rural industrialization, or the process of extending industrial operations to rural areas, presents a second set of problems arising out of the high priority accorded in our economic plans to the utilisation of manpower resources through creation of additional employment opportunities in industries or occupations in rural communities. These are primarily the problems of the sector as a whole engaging the attention of the planning authorities and are unique to this sector. They have no ready solutions at pre-

sent. They may be called problems of utilisation of manpower in rural industrialization. The two sets of problems are distinct since the objectives, approach and methods for seeking solution are different.

Decentralised Pattern

The rural sector of industries is comparatively less developed than the urban and other industrial sectors. Its development has been sought through planning and execution of programmes for rural industrialization. The two most important *a priori* considerations in planning are creation of industrial employment in a proportion larger than would normally be available and the raising of living standards of the rural people through introduction of higher industrial productivity. The normal course of industrialization in the developing areas is through extension of industrial activities carried on in the contiguous developed areas. In the case of the rural areas industrialisation is brought about normally through extension of the urban pattern of industry. The industries most suited for this purpose in the initial stages are the processing industries for agricultural and allied raw materials. The urban or modern forms of these industries represent generally large-scale organisations with a capital-intensive and employment-sparing technology. While extension of these industries to rural areas will solve the problems of industrial productivity it may not solve the problems of creating additional employment. The immediate and long-range prospects for rural industrialization thus present a conflict between the economic objective of raising industrial productivity and the social

objective of utilising manpower resources. The conflict has been sought to be resolved through projecting a decentralized pattern of industrialization.

Though much thought has been given to the evolution of a decentralised pattern of industrialization, no concrete picture has yet emerged. A static picture of it is the dispersal of relatively small or small-scale industries in rural communities and the creation of employment on an aggregate basis. However a more dynamic picture is to regard it as the allocation of available resources to secure economy and employment on an optimum scale. The question whether the decentralised pattern can be established as a dynamic industrial reality in the perspective of modern technological advances is still to be answered. Though economic measures such as financial assistance and protection are considered essential for promoting decentralization of small and small-scale industries the question whether it requires the active participation of industrial scientists and engineers in the field of industry in the manner required for developing large-scale industries has not been given the consideration it deserves. It has been suggested that "research" is involved in solving the problems of industrial decentralization. But the nature of research in terms of current methodology for scientific and industrial research, the agencies for conducting such research and the application of its results to the vast field of rural industrial development has not been explained. The concept of decentralized pattern of industrialisation thus remains largely a theoretical one which is of interest to economic analysts but is beyond the com-

prehension of the bulk of practical-minded scientists and engineers and rural producers

Research and Development

The lack of interest on the part of scientists and engineers in the decentralized pattern has sometimes given rise to the criticism that they are not endowed with a "social conscience" to motivate them sufficiently to be attracted to the rural industrial sector and direct research to its problems of development. Such criticism arises partly from lack of full understanding of the process of industrial development in the developing economies under the influence of scientific and technological advances. It is partly due to confounding or identification of the problems of industrial productivity with those of utilisation of manpower resources in rural industrialization. In the context of modern advances in science and technology, the problems requiring research in the developing rural sector are concerned with utilising technology to obtain the best possible economic and social outcome and not advancement of technology. The problems have to be solved in the field of industrialization itself.

The criticism reveals that there still persists in our thinking the nineteenth century position of "physical science *versus* social science" though such a dichotomy has long since disappeared by the growth of the borderland sciences and the development, since the Second World War, of scientific techniques derived from both physical and social sciences for application to social objectives. The research that the critic has in view is research as understood by the common man and associated with spectacular scientific discoveries and technological inventions. This is called "research and development" in current terminology. Research and development, or scientific re-

search leading to development or advancement of industrial technology, is the main creative process through which modern industries are advancing to attain higher productivity or diversifying their activities to secure greater utilisation of natural resources and to widen the range of industrial products. It is a two-stage process completed by two different agencies. At the first stage, called applied scientific research, scientists working in research laboratories discover new applications of science to industry. At the second stage, called technological development or technological research, engineers working in industrial equipment manufacturing industries utilise the new applications of science to develop new technology or improve existing ones.

Some Misconceptions

It is through organised research and development that phenomenal advances in science and technology have been made in the present century. Research and development opens out possibilities of starting new industries and stabilises the old ones. The comparatively new industries that have originated entirely through scientific advances are modern chemical processing industries, electronic industries, advanced engineering and metallurgical industries, nuclear industries, etc. Old industries are those which had their origin in the pre-industrial crafts and which have in passing through the industrial revolution between 1750 and 1850 enlarged their scale of operation and stabilised the technology first developed through application of engineering and later rationalised through application of science like textile industry using natural fibres, vegetable oils and fats, sugar, leather, paper, ceramics and other processing industries for agricultural, dairy and food products. These old industries are most suitable for

rural industrialization since the processes are relatively simple and the raw materials are of rural source

Technologically underdeveloped industries, such as our traditional village industries, cannot advance through research and development but can make progress only through modernisation, or progressive adoption of modern techniques. The methods of applied scientific and technological research cannot be applied to industrial decentralization. They cannot be extended to solve the problems of social adjustment resulting from technological change. Therefore, the suggestion made sometimes that research in rural industries should be directed towards making scientific discoveries and technological inventions which should steer clear of undesirable social and centralised implications of modern technology is meaningless. To expect this from research scientists or research engineers would be to expect near-miracles from them. Most of the scientific discoveries and technological inventions have an economic motive behind them. The social implications arise from the motive and the context in which they are utilised by man. The decentralized pattern, if it can be achieved at all, can be achieved only by utilising modern technology. The paradox needs little labouring to establish that the problems of utilising manpower resources through employment in rural industries have arisen in our developing economy not due to lack of scientific and technological research but due to our failure to understand how to utilise their accumulated results in the form of modern technological developments to obtain the best possible economic and social outcomes.

The problems facing us today have been

usually traced to the technological development of mechanical sources of power which occurred more than a century ago during the industrial revolution. Since then science and technology have advanced at a very rapid pace. Their rate of growth is much faster than the rate of growth of populations. The problems raised by the technological advances representing automation in our own times, which have been considered to have touched off a second industrial revolution (the Cybernetic Revolution), have yet to be faced in our industrial economy. To consider, in this perspective, that the problems of rural industry are the problems of research for advancing technology is to be highly unrealistic.

Planned Utilisation of Technology

A realistic approach, however, is to regard them as problems of planned utilisation of modern technological developments together with other resources to ensure optimal or best possible employment opportunities. The decentralized pattern and the more recent concept of an "intermediate" technology represent this optimum. There is no alternative to planned utilisation of modern technology in rural industrialization other than haphazard or unplanned utilisation by extending the urban pattern of industry to rural areas. The utilisation of modern technology to solve the very problems raised by it may appear self-contradictory. But there is no contradiction if it is realised that the social implications of modern technology are not inherent in it but are dependent on the manner of its utilisation.

Industrialization in every sector occurs by "borrowing" technology together with organization from developed sectors. Every

industrial sector, from steel and basic industries to small-scale urban industries in our developing economy is borrowing technology from advanced or developed countries. The rural sector is no exception. It is borrowing technology from the more developed urban sector. This is a decentralized process brought about by the decisions taken by the producers themselves. In the normal course the enterprising producer is assisted in taking decisions by manufacturers of industrial equipment ranging from small flour mills to large solvent extraction plants. He has no technical know-how and relies entirely both for technical know-how and industrial equipment on commercial sources. The example of other producers who have succeeded gives him added confidence. Therefore, industrial organisation and technology tend to be repeated in toto with no regard to the best possible course for utilisation of available resources. The only effective strategy of planning is to direct the process of rural industrialization at the place where it occurs, viz., at the community development block level to ensure an optimum utilisation of resources including manpower and technology.

Technology is the most potent resource and the controllable independent variable in the dynamic process of industrialisation considered as a whole of which economy in production and employment are dependent variables. If technology can be controlled employment can also be controlled. But control requires the organization of technical services at the block level consisting of scientists, social scientists and engineers trained in modern methods of industrial planning, which provide combinations of the methods of physical and social sciences. It is by applying these methods that technological advances can be utilised on a planned basis to

obtain the best possible outcome in the form of economy in production and increased employment on higher remuneration.

The result of such an organization of technical services, the function of which is very similar to the technical and consultation services available to the most advanced industries being developed in the public and private sectors according to the five year plans, will be to bring the entire creative forces of modern physical and social sciences to bear on the economic and social advancement of the millions of our people living in utter economic and social stagnation. The establishment of panchayat raj, signifying the delegation of authority for rural development planning to the local democratic bodies, has rendered possible the organization of such technical services on a scale and quality which has not been possible in the first decade of our economic planning.

Industrial Planning

What are the newer methods of industrial planning available for application to programmes for rural industrialization to ensure the creation of the maximum possible employment opportunity? The greatly accelerated pace of scientific and technological advances of the present century and particularly since the Second World War has created new problems for industry and all other activities affected by these advances. These are the problems of decision or planning which an increased complexity of organised activities with their conflicting economic and social objectives have created. The most striking illustration of this problem is furnished by the development of nuclear energy which can be used either for the benefit of humanity or for its destruction. These problems have no

methods of solutions either through physical sciences or social sciences

The remarkable developments of the borderland sciences in recent decades, Particularly, the branch of statistics known as "statistical decision", has enabled existing techniques of physical and social sciences to be combined to deal with the problems of conflict and seeking optimal or pragmatic solutions. The conflict between the economic objective of higher industrial productivity and the social objective of large employment in rural industrialization is a problem of conflict which can be dealt with by this method. Hitherto there has been no common approach between physical and social scientists. This new method, called somewhat non-committally, "operational research" by scientists provides the common approach. Its scope ranges from economic, industrial and social planning on a state-wide basis to traffic control.

Operational Research

The pattern of conflict in rural industrialization is the "optimal allocation of resources under restraints". The scope for operational research in rural industrialization is in the main restricted to this pattern of conflict. Therefore, the selected techniques applicable have been called industrial planning which includes formulation of linear programmes and dynamic programmes. The techniques of industrial planning can be applied to the development of traditional village industries or to the decentralization of modern industries. They can be applied to regional planning including both traditional and modern industries and agriculture. The detailed illustration of application to specific industries goes beyond the scope of this article.

Operational research provides the only methodology available today for application of

science, and its product, technology, to social objectives. It is through this methodology that scientists and engineers can participate actively in programmes for rural industrialization. The word research used to describe what constitutes planning may appear intriguing. The difference between research and development and operational research is that while one is developmental the other is evaluative. Research and development is concerned with the search for and development of new technology which has a higher productivity than the existing technology. Operational research is concerned with the evaluation of existing and new technologies for the purpose of utilising them on a planned basis to realise the pre-determined economic and social objectives. Research and development is the research most useful for an affluent society. Operational research is the research essential for the advancing millions. However, the application of operational research to rural industrialisation requires no less scientific and engineering talent than research and development. While we have more than a score of national laboratories for scientific research leading to technological advancement, we have as yet no comparable organisation for evaluation and utilisation of scientific and technological advance for the economic and social welfare of our rural millions. Such an organisation may be mistaken for large and imposing buildings and expensive scientific and engineering equipment if we identify problems of raising industrial productivity with the problem of utilisation of human resources through rural industrialisation. It consists essentially of scientific and engineering personnel of talent and leadership to be mobilised for a task of the largest magnitude facing national planning.

Bombay
15 July 1963

A NEW LOOK AT INDIA*

G S RAYCHAUDHURI

RURAL industrialisation is a massive problem in India. How massive it is becomes clear when we look at the dynamics of Indian rural population. Of the 439 millions in 1961, 360 millions were found living in over five and a half lakh villages. These teeming millions are increasing at the rate of nearly two per cent per annum. And further, as the rate of urbanisation in the last decade reveals, there is little chance for any significant portion of this now 375 millions to be accommodated in the urban sector. In other words we should view the problem of backlog in unemployment separately for rural and urban areas.

It is against this background that Messrs Lynton and Stepanek have viewed the problems of *Industrialisation Beyond the Metropolis*. There are quite a number of bottlenecks obstructing the spread of industrialisation beyond the metropolis but nevertheless it has been suggested that to cope with the problems of poverty and unemployment India should treble or double her rate of industrial growth. To achieve an average rate of industrial growth between 15 and 20 per cent per annum (1956 as base year) the rate of capital investment should also be stepped up to a considerable extent. Any guess about the volume of capital necessary for this task depends on our knowledge of capital-output ratio. And this can some-

what be derived from our choice of investment sector and technique of production. The same choice also tells us about the employment position. A highly capital-intensive technique calls for increase in investment without proportionate increase in employment. But since in India it is necessary to increase both output and employment at a high rate the authors of the booklet have put forward a case for a new industrial development policy. The main features of this policy are (a) choice of a district rather than India as a whole as planning unit; (b) emphasis on skill-intensive 'intermediate technologies', and (c) encouragement of people's participation in development through reorganisation of local institutions.

District Plan

The choice of district as planning unit should be considered not merely as a problem of location of particular industries but as integration of spatial problem in the body of planning. The logic of the classical theory that development follows industries is being reversed here as industries follow development. This is because the so-called 'spread effect' of economic development as a consequence of concentration of industries has been observed to be of limited significance. Moreover, the pattern of economic development close to a region having heavy concentration of industries generally reflects the gross inequality of income and wealth.

* R. P. Lynton and J. E. Stepanek, *Industrialisation Beyond the Metropolis—A New Look at India*, Hyderabad, 1963, Pp vi, 44, (Mimeographed), Price not mentioned.

distribution. So it is not merely to utilise the idle resources of a district but to initiate a stable and balanced regional development that we should start with a 'district profile' and then transform it into a 'district plan'.

But there is another side of the picture. In the short run, i.e., till sufficient social overheads are built up in villages, any attempt to manufacture standardised goods in rural areas is bound to end up in higher cost per unit. The authors, however, feel that though private cost of such manufacture would be higher the total cost would be lower, because, in their opinion, after a certain point of development cities generally provide external economies to industries and other advantages of living only at a high cost. Though this is true, in underdeveloped countries this may be true not because cities have reached a saturation level but because cities are mostly unplanned. And, therefore, in the short run, there is a problem of choice between replanning our cities and providing subsidies for rural decentralisation. Much depends on, and here the reviewer agrees with the authors, "quantitative research to establish the relation between public and private costs for different kinds of manufacture."

"Intermediate Technology"

For employment the authors have suggested the choice of skill-intensive intermediate technologies. This is in consideration of the fact that India can neither mobilise such huge investment as to take care of all surplus labour with capital-intensive technique nor depend on traditional technique to raise her industrial productivity. Hence this compromise of intermediate technology—a compromise which must work out successfully both in terms of the mechanism and value. But surely this technology will

not cause the productivity to rise as much as would have been possible under modern technique in that case the developed countries would feel the necessity of imitating intermediate technology). Then the question arises how intermediate the intermediate technology would be? Will it be possible to modify the technology to achieve a certain maximum productivity rate within our limits of financial investment? Much depends on the mechanical possibilities. Now even if one agrees to this as a short-run possibility one does not know what shape it would take in future. Because when today's underdeveloped countries would be able to adopt today's modern technology they would, perhaps not to their surprise, find that technology to be traditional compared to the technology of developed countries of that time. Or one may happily think that at a certain point of history the rate of growth of underdeveloped countries would far outstrip the rate of growth of the present developed countries so that they may be technologically at par with them and the population growth in underdeveloped countries would enter the phase of decline in demographic cycle and thereby solve the problem of unemployment. And therefore we must wait and watch.

Consultant and Cooperatives

All this is regarding what is to be done. But there is another question—how is it to be done? The two authors are quite emphatic on these: (a) there must be a key consultant in each district and (b) in industrial organisation there may be cooperative enterprises, branch factories and joint enterprises of various kinds between units in urban and rural areas. The institution of consultant is the most important one because he "needs not only high technical qualifications,

but also substantial work experience with modern technology. On top of these, the stamina, initiative and creativity of someone able to keep going without much day-to-day external support are essential." This consultant will have varied work from providing technical advice to pinpointing potential and promising industrialists.

If we can obtain the services of such a pioneering type of 'unusual man' there is nothing like it. In fact we too have an idea of an omniscient man in our concept of 'village level worker' in our community project schemes. But compared to our village level worker this consultant is technically more qualified and high salaried. Our village level worker has clearly failed in this task, but that the consultant will be able to succeed because of his superior technical knowledge and high salary is also a doubtful proposition. Because economic development of rural areas is not merely an economic proposition—it involves both sociological and political problems. And our bureaucracy being largely influenced by

political weather cannot guarantee the proposed freedom to the consultant. On the other hand a society of the type that we have in our villages riddled with various types of factions and inequalities cannot be responsive to mere economic stimuli. To be frank, between either apathy or domination of bureaucracy and village politics the work of the consultant may not be exciting at all. In the matter of various kinds of industrial organisation and financial institution one must carefully note the historical condition of their growth. In a democracy these institutions can never grow so long as the anti-forces are in a dominating position. And it is in a democracy sometimes that even the diagnosis of these anti-forces becomes quite embarrassing. Nevertheless the reviewer fully agrees with the authors on the necessity for some sort of consultant and various economic institutions with only this addition that the government should create sufficient legal and political condition to foster their growth.

New Delhi
24 August 1963

Capitalist production, when considered in isolation from the process of circulation and the excesses of competition, is very economical with the materialized labour incorporated in commodities. Yet, more than any other mode of production, it squanders human lives, or living labour, and not only blood and flesh, but also nerve and brain. Indeed, it is only by dint of the most extravagant waste of individual development that the development of the human race is at all safeguarded and maintained in the epoch of history immediately preceding the conscious reorganization of society.

Karl Marx *Capital*, Volume III

PROBLEMS OF WOMEN'S EDUCATION.

S SHRIDEVI

While the spread of women's education and improvement in their status especially after independence, have been welcomed, they are also believed to pose a number of problems. The economic independence which education has brought to women, is fraught with undesirable consequences for family life including children's upbringing. This has led to the reappraisal of the objective, content and programme of women's education.

ONE of the most impressive achievements of India in recent years is the spectacular growth of women's education. Indian society which until six decades ago considered girls' education utterly unnecessary has completely reversed its attitude and is now convinced of the need for providing them with education at all levels. Today large numbers of women are going to schools and colleges not only for the sake of general education and culture but also to pursue various professions like teaching, nursing, medicine, commerce, engineering, law, journalism, etc. The forces that have brought about this expansion of higher education of women, cannot be traced to any immediate tangible factors. A number of powerful currents of ideas that swept through the country during the latter half of the 19th century as a result of certain indigenous movements towards religious and social reforms have contributed to this development

Change in Status of Women

These movements could be described as a challenging response to two outside factors, the advent of British rule and the arrival of Christian Missionaries for evangelist work

in India. The British administration with its imperialist tendencies, along with the proselytizing policy of the early Christian missionaries was deeply resented. The nationalist movement particularly under the leadership of Mahatma Gandhi, who was deeply interested in efforts to improve women's status, was such a tremendous force that women themselves were encouraged to take up their own cause and work for it. This ushered in the Feminist Movement which although late in appearance, constantly agitated for women's rights and education. Then there was the Ramakrishna Mission and the Theosophical Movement which also included emancipation of women in their general programme of work. The result was a flood of activities which brought about all of a sudden a very favourable change in the status of women and finally their emancipation.

This emancipation of women coupled with rights of property and divorce and other privileges for equality with men during the last 15 years since independence has caused a silent revolution with tremendous changes affecting women in different class-

es Among the higher classes which constitute a small percentage of the population, women's education has been mostly ornamental, although a good number of women belonging to these classes has been devoting themselves to many a public cause. Among the middle and lower middle classes education and freedom have brought about a number of changes some of which are beneficial while others are feared to pose a threat to family happiness.

Women in Employment

The most glaring change is the phenomenon of a large number of educated girls both married and unmarried in employment. In the beginning there were only unmarried women in service and that again only in the fields of teaching and medicine as there were no other openings for them at the time. But today conditions have changed and women are in almost every walk of life and even married women encouraged by other women's example and unmindful of conditions in their own families are tempted to enter service. With the increase in demand for labour particularly after the launching of the five year plans—which have further extended the scope for employment in every field of activity—a number of educated women are engaged in full or part-time employment. This has certainly given women economic independence which in its turn has brought about a favourable change in the marriage market relieving the anxiety of parents over incurring heavy expenditure on payment of dowry. The recent law against dowry has no doubt improved the situation. In the case of women enjoying economic freedom marriage is no longer an economic necessity but has become a matter of one of their choice. This has broken off barriers of insular community outlook and

is leading to happy intercaste and even inter-communal marriages. This does not, however, mean that all educated girls of the middle and lower middle classes are happily married. Some young men still secretly desire dowry! Some of the working girls are, therefore, compelled to remain unmarried notwithstanding the vigorous efforts of our social reformers and Government to stamp out this outmoded custom. Then there are also the late marriages where girls marry unwittingly or unwittingly married men with their wives living or dead. In the new Hindu Marriage Act women are protected against polygamy.

Threat to Family Life?

The women's emancipation has, however, been held to be responsible for the breaking up of the family ties. Though there are many major causes for this, the desire of young educated couples to set up their own homes is regarded as one of the main causes. The old family cultural pattern is destroyed, and with it the various virtues that joint families were believed to inculcate. Further it is said that the present system of education which has still certain vestiges of western ideas, has given our women a western outlook that has made them individualistic, a quality considered altogether alien. This new feature is alleged to be disrupting the older type of family because educated girls are becoming sophisticated and are no longer interested in the social and religious traditions either of the country or of the family. They are caricatured as highly romantic persons who seem to be more fascinated by cheap and vulgar films and other exciting adventures rather than devoting their attention to useful work at home. The social and cultural life of the family is, therefore, said to be in jeopardy. While

this may be true to a certain extent, it has to be accepted that the modern young woman is caught between two worlds—a dying old world and the recently born one. She is certainly adjusting herself to this situation. She is often torn between the family life and the occupation she has taken up. In her endeavour to overcome the stresses and strains of this life she is becoming both a mental and physical wreck. Some are worried about these conditions. There are others of course who feel that women's education is very essential for better progeny and for a better world. These two groups represent two radical schools of thought and each has its own following.

Considering the pessimistic assertions of one group, one would wonder whether developments have come to such a sorry pass. It has, however, to be admitted that graduate wives taking jobs have created a problem of reconciling the rearing of family and the pursuit of a full-time occupation, for, children need to be given all attention and care. Doctors have observed that children who have been intermittently left in the care of others have developed peptic ulcers, swelling of the feet and such other disorders. So children should not be allowed to experience lack of love or inadequate parental attention.

Children's Upbringing

At the same time psychologists tell us that there should not be too much of protection in the sense that children are not allowed to "outgrow their baby needs." They should be given a certain amount of independence. Mother's dominance over them could never be beneficial to children. Alva Myrdal and Viola Klien in their book *Women's Two Roles* say, "Between the scylla of rejection and the charybdis of over-

protection the education of a child steers an uncertain course. It is probably best for parents not to meditate over much on these dangers lest their natural confidence be destroyed by self-consciousness. "Since in the field of parental upbringing the extraordinary situation exists that the product is in a position to judge the producer as well as the process of production, it is almost futile to aim at perfection. Once they are old enough to read psychological literature, many children will any way blame their parents for committing one or the other sins or both."

Prospects for Future

The other point of view that women's education is essential for better progeny and for a better world is and ought to be true, for all educational training is not expected to go waste. Women as mothers have an important role to play. Education for them is even more significant than for men, for they have the responsibility of raising the family and giving good education to their children, the citizens of tomorrow. Education should be such as would help them do well both at home and in the community. When India becomes highly industrialised as the United States and the United Kingdom, women will be able to manage both home and office with much less difficulty as there will be many new and improved household conveniences to help them save time and energy. It is interesting to note, in this connection, the happy prophesy of John D. Durand, in his article on 'Married Women in the Labour Force,' that by the continual flow of the newly invented gadgets there will be a day when there will be no home as a place of work and housewives as a functional group of the population.

Moreover, with the popularisation of family planning, work will be further reduced

And yet the problem remains the same, for, home and children are bound to be neglected and children if they are to grow well need a good deal of maternal attention—particularly the attention of an educated mother at that—as the cultural, moral and spiritual habits of men and women are determined in the early years by contact with the mother. “So if the mother is educated,” as Dr Radhakrishnan observes, “and is open-minded, inquiring and alert, looking behind rumour and tradition to find the facts concerned with the course of events, informed about the value of the world around her and interested in it and acquainted with history and literature and enjoying them, then her children will learn these interests and attitudes from her. The educated conscientious mother who lives and works with her children in the home is the best teacher in the world of both character and intelligence. In a society made up of such homes children starting to school already have a background of information, understanding and culture which results in their getting more benefit from school than otherwise would be possible.”

Effects of Mechanization

But the crucial question is whether with the enormous leisure resulting from the use of labour saving devices, women will once again be tempted like our American sisters to sell their leisure either to save themselves from boredom or to earn more money? If they do, the problem of correct upbringing of children will become the responsibility of schools. American schools are seriously contemplating on introducing a curriculum suited for this double role. It was perhaps these consequences that made Gandhiji

shudder at the thought of large-scale mechanisation. Our future depends on the extent of industrialisation in the country and how far women protect themselves from mechanisation invading their homes

Use of Leisure

Presuming that educated women with plenty of leisure decide to stay at home and look after the house and give full attention to the upbringing of their children, there will still be the danger of their being frustrated if not bored, for, there will be no outlet for their education. The meaning of their education will be lost and they will begin to lose interest in education and in the long run women will be as ignorant as they were a hundred years ago. Women, therefore, must do some work, besides their domestic duties. Such work could be a part-time job for two to three hours a day so as to bring her home early enough to discharge her domestic responsibilities. If part-time jobs are assigned to all educated women, it will tie them to jobs of small significance where they will not be called upon to use their mental faculty. If, on the other hand, women wished to be chief executives or doctors or lawyers they should be prepared for a career and the returns will be doubtless to their mental satisfaction and give them a sense of fulfilment. But this takes us back to the problem posed at the outset.

To get out of this vicious circle special education for women has been suggested as a sort of panacea. Various opinions have been expressed on this question. The controversy is over the value of special subjects for women—whether to limit the area of studies in view of the limited physical capacities of girls or to have an entirely separate curriculum for girls with home

science and allied subjects. An entirely separate curriculum for girls forebodes many dangers. Their knowledge will be limited to that of housekeeping and that will retard women's progress in India. Practically it will mean a setback to women's education. The nation will lose half of its human resources by restricting women's education to a limited field.

This is not to argue against the introduction of special courses of studies for girls. There can certainly be special courses provided there is no restriction on other subjects. Women's taking special education can moreover never succeed in keeping woman bound to her home. Emancipation and equality of rights with men will mean some interest for woman outside the home. As the bearing and rearing of children are her responsibilities she will always find work at home. As Miss Deighton Pollack says "In spite of much progress towards equality, life remains and will probably remain more difficult for a woman than for a man." She will have to plan and adjust herself to these

two important roles. Facing the same dilemma in the United Kingdom, the Royal Commission on Population expressed the opinion that "It would be harmful all-round to the woman, the family and the community to attempt any restriction of the contribution that woman can make to the cultural and economic life of the nation. It is true that there is often a real conflict between motherhood and a whole-time career. Part of this conflict is inherent in the biological function of women, but part of it is artificial and the persistence of this artificial element tends to depress the status of motherhood into that of an inferior alternative to outside employment or public life. We, therefore, welcome the removal of the marriage bar in such employments as teaching and the civil service and we think that a deliberate effort should be made to devise adjustment that would render it easier for women to combine motherhood and the care of a home with outside activities."

Hyderabad
5 August 1963

From the frequent episodes in the Upanishads in which the Brahmins are described as having gone to the Kshatriyas for the highest knowledge of philosophy, as well as from the disparateness of the Upanishad teachings from that of the general doctrines of the Brahmanas and from the allusions to the existence of philosophical speculations amongst the people in Pali works, it may be inferred that among the Kshatriyas in general there existed earnest philosophic enquiries which must be regarded as having exerted an important influence in the formation of the Upanishad doctrines. There is thus some probability in the supposition that though the Upanishads are found directly incorporated with the Brahmanas it was not the production of the growth of Brahmanic dogmas alone, but that non-Brahmanic thought as well must have either set the Upanishad doctrines afoot, or have rendered fruitful assistance to their formulation and cultivation, though they achieved their culmination in the hands of the Brahmins.

Surendranath Dasgupta *A History of Indian Philosophy*

SOME ASPECTS OF URBANIZATION IN BENGAL

MITRA GUHA

With the advent of British rule the rural economy in Bengal as elsewhere in India was severely shaken. Agriculture was commercialised and artisans and merchants were deprived of their traditional avenues of earnings. The population from the countryside migrated to new industrial centres and adopted new patterns of livelihood. This process of urbanization brought about a change in human relationships also.

THE process of urbanization in Bengal involves changes which have been impressed upon a rural autarchy. Within this rural base there is a functional interdependence whose aim is self-sufficiency. The pattern, consequently, is one of small agrarian communities interspersed with larger groups of artisans engaged in specific cottage industries. Spatially this is composed of villages with single or multiple functions linked with the handicraft centres by a system of contact through weekly markets or seasonal fairs. The former serve a cluster of few villages within the range of a small area, while the latter serve a wider field. Such fairs are often connected with a religious occasion, but economically are most significant as the foci of exchange for several adjacent districts.

Old Economy Changes

Change in this pattern of life has been effected in several ways. But before we can study this in the concrete, it is necessary to understand some of the deeper factors involved. A change of economy is the main background, and historically it is linked with Indo-British economic relations in the past two hundred years.

By 1757, the British had succeeded in ousting other European competitors, and

they exercised a monopoly in the trade of the country by means of extending their political power. In the first stage of this process, agriculture was commercialised, and plantations of silk, indigo and the like became British monopoly. It is interesting that the new trade also attracted Indian capital which occasionally formed an alliance with British capital. However, a later policy of protection to British trade and enterprise displaced these Indian merchants, who were offered the bait of land instead by the Permanent Settlement. This policy of protection also dealt a death-blow to the handicraft industries, and the artisans were deprived of their hereditary occupations. The old Indian economy was severely dislocated. The final stimulus to the reorientation of production centres in the new economy was given by the introduction of steam traction. The population that migrated to these new centres showed selective tendencies based on the particular opportunities offered to them. The Bolpur-Raipur-IIambazar area offers a suitable illustration in this respect.

Bolpur-Raipur-IIambazar

This area lies along the northern bank of the Ajay river which forms the southern boundary of Birbhum district. The river

bank at one time was lined by several trading stations like Supur, Raipur and Ilambazar. The importance of the river was as a means of transit towards Katwa on the Ganges. When the *diwani* of this area was ceded to the East India Company in 1765, commercial enterprise in the hands of the British began and the investment in a silk monopoly was as high as 4½ to 6½ lakhs of rupees. Indigo cultivation was introduced by a British agent, John Cheap, and factories were established at Surul and Supur.

A member of a prosperous Bengali Kayastha family of Raipur, Shyamkishore Sinha, served as an agent to the East India Company and supplied textiles to John Cheap for export to Europe. Sitikantha, a grandson of Shyamkishore also entered into partnership with Henry Erskine in an indigo factory near Raipur. In identifying their fortunes with the East India Company, the family amassed great wealth and soon became zamindars or landlords. The sons of Sitikantha were sent to England for education. One of them became a lawyer and was the first Indian to be raised to the British Peerage. Other family members, subsequently, received English education and rotated to the city of Calcutta with employment in the various professions offered there.*

The indigo industry declined, however, on account of competition from synthetic dyes produced more cheaply in Germany. So that by the end of the 19th Century all the factories closed down, and the erstwhile flourishing centres of Surul and Supur declined. At this time a new factor emerged which left its impress in a further shift of

location of urban centres. In 1855, the East Indian Railway constructed a shorter route connecting Bengal with the regions of northern India, and this railway cut across the Ajay in a north-south alignment. The district of Birbhum has always been a good producer of surplus rice, and during the first world war, when the price of rice rose, rice-milling became a very profitable enterprise. New centres of rice milling grew along the railway line, like Gushkara, Bolpur, Ahmedpur and Santhia. Bolpur, in particular, was raised from its insignificant position of a small village, six miles east of the old indigo centre of Supur, to its present importance as the foremost rice-trading centre in the region. A good-sized labour population has come into the town, while a seasonal influx of Santhals, who work during the sowing and the harvesting periods, is characteristic of the countryside. Bolpur itself has grown very rapidly in fifty years, from a population of 3,831 in 1901 to 14,802 in 1951. The built-up area has spread from a small nucleus in the south, on the road to Ilambazar, in all directions northwards, engulfing neighbouring villages like Bandgora and Trisulapatti within its municipal confines.

Adra-Raghunathpur

Let us now take an example of a change in the character of livelihood pattern, caused by the development of a railway town in a predominantly rural area. Raghunathpur which is a very old village in the Manbhum district was the headquarters of the Raja of Panchet. Historically, it appears as a small *chatti* or post-station on the Gaya-Benares

* Nirmal Kumar Bose, *Modern Bengal*, 1959, Pp 20 to 23.

† The area was collected by Kun of the Department of Geography, Calcutta University.

road from Bengal. Sri Chaitanya (1485-1533) used this route when he made the pilgrimage to Gaya on foot. To the south and east of Raghunathpur are several small villages which are also very old. There are many brick temples in the Vishnupur style in the four villages of the Arrah mouza on the east, and they are situated on the route to Bankura and Burdwan. The original population of the region was made up of the following: the Raja of Panchet had settled five Brahmins from Kanauj (U. P.) to act as tax-collectors as well as priests, giving them land in the Arrah mouza. The Brahmin families of today claim descent from these. The Bauri caste was the original population here, and they were appointed as palanquin-bearers by the Raja. Besides these, there were also the other castes like blacksmith, potter, fisherman, carpenter and oil-presser, each following his own profession.

The presence of important ore deposits in the neighbourhood, also in the Joychandi Pahar in Raghunathpur, brought about a new design in economic utilization of the area. With a view to making industrial use of these raw materials in the future a railway was built across the region to connect the ore producing regions of Singhbhum with the coal of Raniganj and Barakar. A new railway town named Adra was established between the mouzas of Kashipur and Arrah, and this has brought about a general change in the livelihood pattern of the population.

The railway settlement has physically extended into two small *tolas* of Kashipur and Arrah—Palasnkola and Panchudanga. Opportunities for employment in the railway workshops have drawn the neighbouring people into the new town. Agricultural activity has languished to a great extent as

have also the old caste occupations. The Bauris are employed as coolie labour or as class IV staff in the railway. The Brahmins who have lost much of their land by the abolition of the zamindari system work as railway office staff or as clerks in the Jharia coal field. The blacksmiths and the carpenters have given up their caste occupations and are employed as railway fitters and welders and railway workshop carpenters. Likewise, the oilpressers have found occupation in the railway, while the Marwari businessmen from Asansol and Raniganj have moved into the sphere of trade. Thus there has occurred a revolutionary alteration in the caste occupations. A very small part of the population still lives by agriculture, while in each family about 75 per cent of the members have been converted into wage-earners in the railway and the mines.

Rishra

The third example is one of a purely industrial unit in the dense ribbon of continued urbanization on either side of the Hooghly river. Bipradas who wrote the *Munasa Mangal* in 1495 A. D. gives an account of the villages on either side of the Hooghly river. On the river bank below Triveni there is mention of Saptagram, Kumarrhatta (Halisahar), Hughli, Bhatpara, Boro (a locality which now lies within the territory of Chandernagore), Kankinara Mularjore, Garuha, Telinipara, Bhadreswar, Champdani, Ichapur, the Dwiganga (Baidyabati Khal), Ramnan Akna Mahesh Rishra, Konnagar, Kotrung, Chanak, Sukchar, Kamarhati, Ariadaha, Ghosuri and finally Chitpur with the temple of Sarvamangala Devi. Along this reach in the river the commercial interests of the East India

Company had become consolidated at Calcutta in the 18th century, in the nucleus which Job Charnock built at the site of Sutanuti, Govindapur and Kalikata. A marked change was brought about in these villages which were either centres of Brahmin learning, small markets, trading settlements, or weaving centres and so on, within the rural atmosphere of the river's banks. This was effected by a rapid development of industry.

By about the middle of the 19th century the value of jute fibre as a packing medium in bulk commodity trade was realised. Bengal held sole monopoly in this crop, so it was natural that jute milling was located along the river bank. From the first mill established at Rishra in 1855 by 1940 there were 101 mills within the Hooghly side. A careful examination of Rishra will explain the processes of urban growth more clearly.

As a village, Rishra had the advantage of proximity to the adjacent village of Mahesh which was well-known for its car festival. Rishra itself was famed for its betel gardens. The old quarters of the present-day town, wards three and four, are marked by tortuous and narrow lanes only 2½ yards wide amidst a well built-up area. There are three caste-wards within this, Baruipara, the Baruis being betel cultivators by tradition; Dhenkipara, the Dhenkis also being betel cultivators, and Chasapara, these being cultivators too. So the character of the old village was that of a community dependent on specialized agriculture. Upon this was imposed the industrial pattern. Rishra was part of the Serampore municipality until 1865, and it was only after the railway station was opened in 1900, that it mainly grew. A scrutiny of the development

of the factory units will be of interest in this connection.

<i>Name of industrial unit</i>	<i>Year of establishment</i>	<i>Number of employees</i>
Wellington Jute Mill	1855	3,861
Hastings Jute Mill	1876	4,500
Presidency Jute Mill	—	—
ACCI (ICI)	1931	1,400
Jayashree Textiles	1944	3,000
Shree Ram Silk Manufacturing Company Limited	1948	300
United Vegetable Manufacturing Company	1948	—
Calcutta Phosphate Company Limited	1948	—
Luxmi Narayan Cotton Mills	1952	1,100
J K Steel	1952	—
Bengal Wire Netting Factory	1952	—
Shree Engineering Products	1960	300
Govind Steel Company Limited	1962	300
Shree Dayal Porcelain Works	1962	—

Industrial development began with jute milling, and was responsible for an immigration of a large labour population. An industrial tradition being already established, it was relatively easy to start other groups of industries. The major development has taken place after independence, and the emphasis seems to be on the production of metallurgical goods of light types. But the main point of observation is that the latter industries are found located on either side of the railway line, while the jute mills with a river side location show the importance of the Hooghly river as a means of transport. Presidency Jute Mill, situated on the

grand trunk road is a concern of later origin but it has its own jetty on the river for the transit of the raw materials. It is interesting to note that 11 of the industrial concerns are in the hands of capitalists from outside Bengal. Some of these were originally British, but were subsequently transferred to Indian hands.

Recruitment of Labour

Physically, this industrial set-up has resulted in the segregation of population. Where land is not occupied by industry, in wards one and two there are *bustees* housing labour. Within the industrial sites themselves are quarters for executives, labour lines and the factory. The land devoted to betel plantation has decreased greatly, most of it now is given over to industrial use. The labour population, in the main non-Bengali, comes from Andhra (women recruits) Bihar, Uttar Pradesh and Orissa and is usually recruited from several castes. The method of recruitment is as follows. The mill maintains contact through a jobber, who may be an employee of the concern, and he is responsible for the recruitment of raw hands from the villages. Naturally, he brings people from his native village, who are often connected by family ties. For his services he charges a small fee to the labour he recruits. Most of the hands thus brought in are unskilled and are then given apprentice training. There are usually several such jobbers in the different sections of the industrial concerns. But in the case of larger industrial units and where skilled labour is required, the method of recruitment is through a labour recruiting officer who is a paid employee of the concern.

Labour recruited in the former way shows a community structure with strong

village ties. Often a particular skilled group has a traditional background of technical knowledge, as in the case of the weavers in the textile mills, who are all Muslim artisans from Uttar Pradesh. Whatever may be the background for the immigration of the labour population it shows distinct preferences for grouping. When not provided with mill housing, this population gravitates towards its own group in 'mohallas' composed of people from Chapra, or Ballia or Patna, or Gorakhpur, or Partabgarh and so on. Mutual aid in times of crises, or on particular social functions like the festival of holi or muharram demarcates these distinctivenesses more clearly. Yet during labour disputes between employer and employee the trade union cuts across these divisions and creates a fresh pattern of loyalties.

Of the original Barui, Dhenki and Chasa population, only 20 families are still engaged in cultivation, while the rest are employed in factories. The Bengali population finds employment as office staff in the industrial units, and is recruited locally or from Serampore, Konnagar and Chandernagore. The economic stratification is placed thus: Labour—non-Bengali, office-staff—Bengali, executives—non-Bengali.

Social Segregation

Social segregation, as in the case of the labour group, is found at higher levels also. For example, a women's association, Rishra Mahila Mandal, is composed of wives of executives from the industrial units in the neighbourhood. There are altogether 36 members, of whom only three are Bengali, the president and secretary both being non-Bengali. In the second instance, the Rotary Club, which represents an area from Bally to

Baidyabatī is composed of professional executives from industries ranging from jute-milling to automobile manufacturing. The total number of members is 21, of whom four are Bengali, while the president is a non-Bengali.

New Economic Stratification

The changing economic pattern has led to the evolution of a new functional order in the spatial distribution of urban organization. The population character also has undergone a complete change. The wage-earner, in the new economic stratification,

has invaded the scene of production, and the community interests show a variety of forms. Some of these have not been freed by the urbanization as in the case of the labour groups in Rishra, where zilla loyalties still persist. The new structure and functions of urbanism have thus initiated a process of change in the patterns of human relationships, in which earlier ties of caste, village or district are slowly subjected to disintegration.

Calcutta
17 August 1963

A born democrat is a born disciplinarian. • Democracy comes naturally to him who is habituated normally to yield willing obedience to all laws, human or divine. I claim to be a democrat both by instinct and training. Let those who are ambitious to serve democracy qualify themselves by satisfying first this acid test of democracy. Moreover, a democrat must be utterly selfless. He must think and dream not in terms of self or party but only of democracy. Only then does he acquire the right of civil disobedience. I do not want anybody to give up his convictions or to suppress himself. I do not believe that a healthy and honest difference of opinion will injure our cause. But opportunism, camouflage or patched up compromises certainly will. If you must dissent, you should take care that your opinions voice your innermost convictions and are not intended merely as a convenient party cry.

Mahatma Gandhi

TOWARDS ECONOMIC SEED COLLECTION

P V SHRIKANTA RAO

Seed collection should be organised in such a way that the seed collector is assured of a proper income and those who have to use those seeds for industrial and other purposes find their product economical

IT is now about five years since there has been a greater realization of the need for conserving the non-edible oilseeds wealth in the country although the programme for the development of non-edible oils and soap industry was launched about 10 years ago by the erstwhile All India Khadi and Village Industries Board. Though quite a number of steps were taken and incentives offered for proper collection, storage and processing of these seeds, the response for "qualitative collection" was rather slow in the initial stages. "Qualitative collection" has to be aimed at taking due notice of the two main mutually contradictory factors, namely, that the seed collector has to be ensured of a proper income and that the economics of the operation of processing of seeds should be acceptable to those who use the seeds for industrial or other purposes. It is no simple task to balance these two factors. An answer to this problem may have to be found by simplifying the technology to suit our method of working. Use of power to any degree required to quicken the process should be profitably resorted to wherever possible. The time factor is an important aspect in all the activities

Increasing Earnings for Season

As it is today, the bulk of seed collectors are entities varying with seasons. Efforts

should be made to see that the seed collectors as well as those engaged in the processing do this work year after year. In certain areas large quantities of seeds are collected or large number of people come forward and receive substantial amounts of money as wages in a short period (say a month), though this is an achievement from the point of view of providing additional earnings to families whose incomes are very scanty, this alone cannot lay the strong foundation which is so vital for any industrial activity. The length of the seed collection season may not be so important a factor as the total earnings of the individual for the season. The problem is to see that these earnings are improved considerably. The organisational structure will have to be so geared as to ensure the fulfilment of this objective.

Seed in Storage

The first and foremost thing is to realize that the term is 'seed collection', although it is the fruit which is first picked when ripe. The use of the word 'seed' is significant in the sense that it is the seed which can be stored for long periods. Hence, the need to convert the fruit into seed. If in some cases, seed cannot be stored, then the kernel will be the seed for practical purposes, but in no case the 'fruit' can be 'seed'.

When the aim is "qualitative collection"

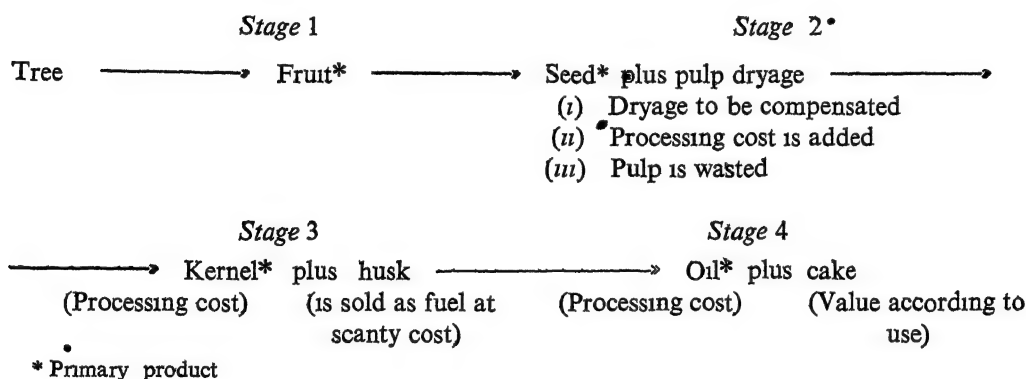
of seeds the cost of collection should be reasonably economic. By 'reasonably economic' is meant that a cost structure should have to be worked out in detail for different species and regions keeping in mind its effect upon the end product. This is possible when the cost of the end product is not susceptible to variations in the prices of established oilseeds and oils. But it is another question whether the price which a farmer gets for his oilseeds is the proper one, taking into account the normal standards of costing, the investments in the form of resources of labour and time.

Success in seed collection has to be gauged from the extent to which the methodology has been able to convert the fresh

'fruit collection' into 'seed in storage'. 'Seed in storage' is a significant phrase which indicates not only seeds collected in large quantities, but also seeds of such a quality that they can be retained in good condition for long periods. This has significance in the sense that the seed stocks should be capable of yielding quality oil that is their oil content should be optimum and the percentage of moisture and free acid should not exceed the critical proportions allowed from the chemical standpoint.

Flow Chart. Tree to Oil

The following is the flow chart indicating the primary product and the end product at each stage.



The tree is the primary source yielding fruits. The fruits are in bunches and found at the end of branches. They fall down from the tree as they become ripe and sometimes even the half-ripe and unripe ones get detached from the bunches on account of strong wind or storm. It takes three to four weeks, at times, even more, for all the fruits to ripen and fall to the ground. The ideal condition should imply picking all the fruits direct from the tree. But since the tree is sometimes very tall, and the fruit

bunches are at the peripheries it is not possible to collect them by climbing the tree as the end branches are not strong enough to bear the weight of a man. Long bamboos with scythes could be used in the case of medium trees. But this is apt to cause damage to the tree. Hence, collection has to be made when the fruits fall to the ground naturally. Cleaning the floor and hand-picking of fruits will eliminate the external impurities which cannot be avoided.

by resorting to collection by sweeping the ground

Quality Collection

Hand picking of fruits should be practised as it is the ideal method whereas the sweeping method is bound to lead to inclusion of foreign material in the collection. This foreign material like stones, twigs and dirt besides raising the cost, has a bad effect upon the fruits if they are allowed to remain in the same condition for sometime. Unripe fruits fall on the ground either because of wind or as part of the bunches of fruits detached from the tree. The colour of the ripe fruit (yellow) is different from that of the unripe one which is somewhat greenish. A discerning eye can easily distinguish this by observing different varieties of fruits. In commercial collection it may be difficult to separate them as it is a time-consuming process.

Seeds of fruits which have their shells damaged, allow air and moisture to penetrate and affect the kernel. The kernel is oxidised and becomes rancid. Hence, care should be taken to see that the shell is not damaged.

The soiled fruit indicates that the pulp has been exposed to dirt and the shell inside may be damaged. Whenever there is storm or rain the fruits which have fallen

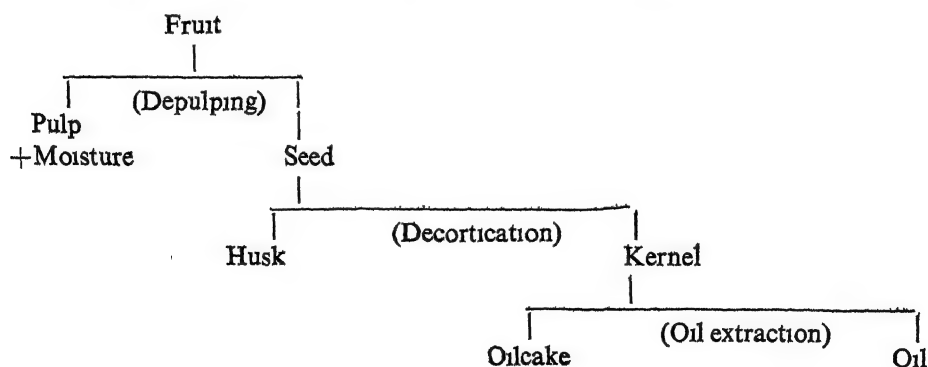
on the ground, generally get soiled. These have to be washed with water and dried soon. But the best thing is to depulp them immediately. Soaking the fruits in water eliminates such of the extraneous materials which are heavier than water whereas others remain floating with the fruits. Sieves can be used profitably to remove these.

Steps should, therefore, be taken in the field, at the time of collection to ensure "qualitative collection". This requires an extension training programme which has to be conducted under patient and expert guidance. It offers ample scope for a study of problems directly connected with the people in the area. If at least this is achieved, the collection of quality fruits is more or less ensured.

The processes of depulping, drying, decortication, winnowing and oil extraction depend upon the technology, methodology, techniques, equipment, machinery and technical ability of the persons concerned.

Use of Bye-Products

There is also enough scope for exploring the possibilities of using the various bye-products obtained in the process, i.e. the different parts of the fruits collected. Taking neem fruit, for instance, the following flow chart shows products and processes at different stages of the activity.



In the first stage, the fruit is depulped and dried. The cost incurred on depulping the fruit can be offset if some use is found for the pulp which the fruit yields. To the extent it can be done, the investment on seed collection is reduced. Similarly, to the extent the economic value of husk and oilcake, the bye-products at the later stages, can be recovered the price of oil the final product, can be controlled.

The cost of processing at each stage—pulp, decoration and oil-extraction—should be minimised. For this purpose the machines and the tools should be efficient so as to ensure optimum output in minimum time.

Developing the Skill

Along with the fabrication of the equipment and tools, the ability to operate them to advantage to secure optimum yield at each stage of the processes involved has also to be ensured. For this purpose, adequate facilities to train persons have also to be provided. There should be a planned programme for introducing improved equipments, techniques and methodology so that the persons who are to utilise them should be able to assimilate the new trends. In this context the steps taken to study the present methodology in vogue and investigate possibilities of introducing improvements in them rather than adopting newer ones will be efforts in the right direction. It will thus be easier, after some time, to introduce improved and newer equipments and techniques. The seed processing observation units set up by the Directorate of Non-edible Oils and Soap Industry of the Khadi and Village Industries Commission is a right step in this direction. These (S P O) units have been helpful in provid-

ing the basic data regarding the methods in vogue.

In spite of the precautions taken, there are possibilities of some of the impurities being retained in the product at each stage. The ideal 'fruit' or 'seed' or 'kernel' should be defined with a permissible percentage of impurities. This will facilitate determining the quality of lots of fruits or seed collected. Prices to be paid for the fruits or seeds should be governed by the quality. There is no common norm for the whole country at present. It varies from region to region. But a common norm has to be determined. The data collected by the seed processing observation units can guide us in this direction.

Sociological Aspects

There are other aspects also to the problem of economic seed collection. With all efforts made to ensure optimum conditions, qualitatively and quantitatively, as well as technologically, it cannot be taken for granted that results could be achieved according to expectations. There is always the element of 'lag behind' when the methodology is applied in the field for the simple reason that the entire follow-up will rest ultimately upon the local persons. There is always the personal factor in the collection and processing activity, depending upon the receptivity and applicability of the standard techniques by the local people. Besides, it should be remembered that seed collection is a dependent function of natural phenomenon and the vagaries of nature upon which it is difficult to exercise control under normal conditions.

Unlike agricultural operations, where the farmer sets himself with certain known factors like the extent and type of land,

available his capacity to cultivate it and then take care of the crop till the time of harvesting when he knows also the approximate yield these non-edible oilseed bearing trees are scattered all over and one has to move from place to place tree to tree, in order to tap and muster the entire resource

Reduces Pressure on Land

Of the total estimated wealth of non-edible oilseeds neem accounts for approximately half of it. Taking this at five lakh tons of fresh fruits the value comes to about three crores of rupees. In all from all non-edible oilseeds over two lakh tons of non-edible oils worth Rs. 28 crores can be obtained besides at least 4 lakh tons of oilcakes which can be used as manure for agriculture. An acre of groundnut crop is estimated to yield about 200 lbs. of oil. Two lakh tons of non-edible oil will be equivalent to 22.4 lakh acres of groundnut crop. The estimated

4 lakh tons of oilcake can be used as manure for four lakh acres of paddy and sugarcane crop.

Hence the need of the hour is to take steps for fully exploiting this resource of non-edible oilseeds. The reasons for our inability to reach the targets have to be analysed. These may be psychological, sociological or technical. Illiteracy inhibitions to take up the programme lack of sufficient pecuniary allurements paucity of finances and lack of economic leadership may be some of them. These will have to be tackled on a war-footing. The strength of our organisation will lie in our preparedness to set right squarely even the smallest fault in our working and our success will depend on the extent to which the programme takes firm roots in the soil.

Bombay
27 August 1963

We are grateful to our readers and contributors who so enthusiastically responded to our invitation for articles for the Annual Number of Khadi Gramodyog. We regret our inability to include all the contributions in the Annual Number due to pressure on space. We hope, however, to be able to publish them in future issues of Khadi Gramodyog.—Editor

DILEMMA OF PROSPERITY*

SUBHASH CHANDRA SARKER

THE journey of man through the thousands of years since his first emergence on the earth has been an arduous one, full of constant struggle and hard toil for survival. Most of human energy had to be spent in securing the necessities of life. Nobody could live in comfort without compelling many others to remain in suffering because the total fund of available supplies was very much limited and could not be augmented. Where few were rich many had to be poor. Until recently this was true of all peoples in all lands. The industrial revolution for the first time opened out possibilities whereby nations could produce enough not only to meet their needs but also to yield a large surplus. Technological developments have made poverty and inequality irrelevant, since neither of these evils is a necessity. That application of modern technology can wipe out poverty to a considerable extent has been demonstrated in more than one country. Similarly, there need be no inequality since it is now possible to produce enough for everybody to have as much as he would.

Continuing Rich-Poor Disparity

Unfortunately these possibilities have not so far been realized in practice universally. The large mass of humanity still lives in dire poverty and inequality has not disappeared even in the most plentiful country in the

world. The geographical distribution of poverty and the character of inequality in the most prosperous countries are of considerable significance. About half of the world's population enjoys only 16 per cent of the total world income, on the other side of the scale only 15.2 per cent of the population appropriates as much as forty-five per cent of the total world income (28 per cent of the total income accruing to as few as 7.7 per cent of the population). As if this was not bad enough, per capita income in poorer countries is known to be growing at a slower rate than in the richer countries so that the divergence between the rich and poor countries is becoming increasingly pronounced. Nationally also in many countries this international trend of greater divergence between different income groups has become gradually pronounced. So that, despite technological possibilities to the contrary, prosperity has remained exceptional as much in the national sphere as in the international sphere.

This is an abnormal situation and must be remedied urgently for the sake of a happy future for man. The problem has two facets—one national and the other international. Within every nation all efforts should be made to raise the standard of living of the masses and to reduce inequality. In the particular context of the present-day world, where the countries have to face a worldwide competition, it is by no means easy to achieve this objective. Many coun-

* *America and the World Revolution* by Arnold Toynbee, Oxford University Press, London, 1962. Pp 77, 12 s 6 d.

tries find it exceedingly difficult to bring modern technology to the service of the people first because they do not possess the know-how and do not command, immediately, the wherewithals with which to purchase the knowledge which, being in great demand, is selling a little dearer than it ought to, in the international market, and second, because the competition not only between the developed and the underdeveloped countries but also between the underdeveloped countries themselves has been becoming keener day by day, affecting the capacity of the latter to develop. To make the second point clear, the India-China conflict has decidedly affected India's pace of growth, as the Soviet-Chinese conflict China's rate of growth. Which leads to the second facet of the problem by underlining the need for international cooperation. The more prosperous nations can make useful contribution in a number of ways. In the modern world two colossi—the USA and the USSR—are striding the face of the earth. Disarmament by the Western Powers and the USSR alone could release vast sums and energy for world welfare, it "would relieve the rich nations of their present fear and the poor nations of their present want" (p 71).

Isolation through Affluence

Dr Arnold Toynbee, in his three public lectures delivered at the University of Pennsylvania in the spring of 1961 which are brought together in the present volume, has dealt with the role of the USA, which commands a gigantic productive force, in the modern world. How far has the USA sized up her responsibilities in the contemporary world and fulfilled these responsibilities? The

USA, Dr Toynbee says, has not acted up to her responsibilities. Although the American War of Independence had evoked a worldwide appeal, the USA, now grown rich, is not enthusiastic about that response which has ushered in an era of revolution throughout the world creating a stir among the down-trodden peasantry everywhere. America, to quote Dr Toynbee, "has joined the minority" (p 17) and has "felt herself impelled to defend the wealth that she had now gained against the mounting revolutionary forces that she herself had first called into existence" (p 18).

Wealth had caused that isolation (It could also be caused by caste, Dr Toynbee, has mentioned an Indian Hindu brahmin professor who avoided taking food with him because he was a non-Hindu Christian). By 1924 the USA had closed its doors to others through the passing of the immigration laws which restricted the immigration of Europeans as well (the Asians never had any freedom of settlement in the USA). "This self-insulation is the inevitable penalty of finding that one has become rich and then taking steps to protect one's new found well-being" (pp 24-25). Yet, what is the nature of that well-being? The present day consumption in the USA was far in excess of people's genuine personal wants ("Our wants are vastly greater than our needs, even when our wants are not inflated by the artificial stimuli of advertising agencies") (p 69). And the wants have been magnified many times more by the advertising industry which had to find out new ways of keeping the vast productive forces, which could not find the natural outlet of producing the necessities for the general welfare and had turned to the production of less

essential commodities, moving "The measure of the difference, in the United States, between genuine wants and actual consumption is given by the scale of the wants manufacturing industry that is carried on today on Madison Avenue (where the leading advertising houses are situated)", Dr Toynbee writes (p 56) The result has not been quite happy

Limitation of Wants a Necessity

Some limitation of this ever-increasing want has become a vital necessity "American way of life is due for a check-up", Dr Toynbee warns, (p 67) because it does not help in realizing the true end of man which is the pursuit of spiritual aims While man's survival depends on the satisfaction of the necessities, seeking satisfaction of wants that are not primary needs cannot be properly made the prime mover in life It is spirituality which makes man human The opening out of possibilities of the eradication of poverty from the face of the earth has brightened the prospects of realizing these spiritual potentialities by making the satisfaction of basic needs much easier than before Starving men, when given food, are prone to glut themselves, but gluttony is not edifying or healthy If the Americans, being the first people to attain affluence, should have been tempted in the first generation to surfeit themselves with consumer goods, it is not difficult to understand that But like gluttony this indulgence is also not healthy and as such is not desirable, it is bound to give way to sanity "I fancy", Dr Toynbee says, "that future generations in the West will look back on this episode

The analysis of the world's greatest living historian deserves to be pondered over with all the seriousness Dr Toynbee was addressing an American audience and had therefore selected the American example to illustrate his point But every nation must apply the analysis to its own sphere so as to rectify its conduct Gluttony, whether American or Indian, is going to produce the same ill results Nothing would be more misleading than to believe that less prosperous countries need not bother about conspicuous consumption We know in India that despite all the grinding poverty, conspicuous consumption has already become a vice The American through his lone efforts cannot eradicate gluttony and inequality, he must have the cooperation of other national groups A great responsibility devolves on the less prosperous societies in this regard In a way, being far removed from the luxuries of the American way of life (which Dr Toynbee defines as the way of luxurious living), the people in the underdeveloped countries are in a better position since they can learn from that experience and avoid the mistakes of an advertisement-run society of artificial wants To us Indians, who have the teachings of generations of sages and philosophers, the philosophy of satiation was for long part of the way of life Of late, however, there have been in practice marked deviations from this cherished practice What is needed is the adoption of concrete steps to ensure its full realization in practice

Bombay
2 September 1963

